MPPSC 2026

सहायक प्राध्यापक

पेपर – II

राजनीतिशास्त्र

POLITICAL SCIENCE

अध्यायवार MCQs

Nodia

Scan QR for Demo PDF

GET ALL STUDY MATERIAL IN ONE APP!

- Textbooks
- Previous Year Chapterwise Question Banks
- 30 Sets Sample Papers
- Worksheets

FREE!

DOWNLOAD NOW!

SCAN & DOWNLOAD

GET IT ON Google Play

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग

2026

सहायक प्राध्यापक

पेपर – II

राजनीति शास्त्र

अध्यायवार वस्तुनिष्ठ प्रश्न बैंक
आयोग द्वारा जारी पाठ्यक्रम के अनुसार

NODIA

Downloaded from www.pdf.tube

MPPSC सहायक प्राध्यापक राजनीति शास्त्र
Edition May 2026
Published by :NODIA
An Imprint of NODIA EDITIONS LLP

Information contained in this book has been obtained by author, from sources believes to be reliable. However, neither NODIA nor its author guarantee the accuracy or completeness of any information herein and NODIA nor its author shall be responsible for any error, omissions, or damages arising out of use of this information. This book is published with the understanding that NODIA and its author are supplying information but are not attempting to render engineering or other professional services.

© NODIA EDITIONS LLP

MRP ₹650.00

This book is available on amazon and flipkart only and not available in market.

NODIA EDITIONS LLP
125, Sector 6, Vidyadhar Nagar, Jaipur 302039
Phone :+91 9001005245
email : mail@nodia.in

विषय-सूची

अध्याय 1.	राजनीतिक चिंतन एवं विचारक	7
अध्याय 2.	राजनीतिक अवधारणाएँ एवं मुद्दे	67
अध्याय 3.	तुलनात्मक राजनीति	129
अध्याय 4.	भारतीय शासन एवं राजनीति	192
अध्याय 5.	लोक प्रशासन एवं संगठन सिद्धांत	251
अध्याय 6.	लोक प्रशासन	310
अध्याय 7.	अंतरराष्ट्रीय संबंध	371
अध्याय 8.	अंतरराष्ट्रीय संबंध एवं भारतीय विदेश नीति	434
अध्याय 9.	मध्य प्रदेश की राजनीति	510
अध्याय 10.	मध्य प्रदेश की राजनीति एवं प्रशासन	573

Click Here to Buy book on Amazon

सहायक प्राध्यापक परीक्षा–2026
द्वितीय प्रश्न–पत्र
पाठ्यक्रम – राजनीति शास्त्र

NODIA

इकाई–1

- प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचार : कौटिल्य और स्मृति पर्व ।
- आधुनिक भारतीय विचार : गाँधी, एम.एन. राय, अरविंद घोष, जयप्रकाश, अम्बेडकर, सावरकर
- यूनानी राजनीतिक विचार: प्लेटों और अरस्तू ।
- यूरोपीय विचार –I एवं II : I– मैकियावली, हाब्स, लॉक और रूसो, II – बेंथम, जे.एस. मिल, हीगेल, मार्क्स और ग्रीन ।
- आधुनिक राजनीतिक विचार– I एवं II : I– लेनिन, माओ, ग्राम्शी, II– राल्स, नोजिक और सामुदायिकवाद ।

इकाई–2

- अवधारणाएँ एवं मुद्दे–I : मध्यकालीन राजनीतिक विचार : चर्च–राज्य संबंध और दो तलवारों का सिद्धांत
- अवधारणाएँ एवं मुद्दे–II : व्यवहारवाद तथा उत्तर–व्यवहारवाद, राजनीतिक सिद्धांत का पतन और पुनरोत्थान ।
- प्रजातंत्र, स्वतंत्रता एवं समानता ।
- वैयक्तिक और सामाजिक न्याय ।
- विचारधारा की भूमिका एवं परिवर्तन के सिद्धांत: लेनिन, माओ, गाँधी ।

इकाई–3

- तुलनात्मक राजनीति का एक अनुशासन के रूप में उद्भव, प्रकृति और विषय क्षेत्र।
- तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के उपागमं : पारम्परिक, संरचनात्मक–प्रकार्यात्मक, व्यवस्था और मार्क्सवादी ।
- शासन के अंग : कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका– तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य में उनके अन्तर सम्बन्ध।
- राजनीतिक विकास और राजनीतिक आधुनिकीकरण।
- राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक समाजीकरण एवं राजनीतिक संचार, राजनीतिक अभिजात और प्रजातंत्र का अभिजात सिद्धांत।

इकाई–4

- राष्ट्रीय आन्दोलन, संवैधानिक विकास और भारतीय संविधान की रचना; वैचारिक आधार प्रस्तावना, विशेषताएँ, मौलिक अधिकार और कर्तव्य, नीति–निर्देशक सिद्धांत।
- सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के साधन के रूप में संविधान, संवैधानिक संशोधन और पुनरावलोकन ।
- संरचना और प्रक्रिया–संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रि परिषद्, संसदात्मक व्यवस्था की कार्य–शैली।
- संघवाद: भारत में सिद्धान्त और व्यवहार, स्वायत्तता की मांगे और पृथकतावादी आन्दोलन, केन्द्र–राज्य सम्बन्धों के उभरते प्रतिमान। न्यायपालिका: उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक सक्रियता जनहित मुकदमों सहित, न्यायिक सुधार ।
- राजनैतिक दल, दबाव समूह, जनमत, संचार माध्यम एवं कृषक आन्दोलन। चुनाव, चुनावी–व्यवहार, चुनाव आयोग और चुनाव सुधार, वर्ग, जाति, लिंग, पिछड़े एवं वंचित वर्ग और क्षेत्रीय मुद्दे, राष्ट्रनिर्माण और एकीकरण की समस्याएँ ।

इकाई–5

- लोक प्रशासन का एक अनुशासन के रूप में विकास, लोक प्रशासन के अध्ययन के उपागम: निर्णय–निर्माण, पर्यावरणात्मक और व्यवस्था विकास प्रशासन।

- संगठन के सिद्धांत ।
- संगठन के नियम : सूत्र और स्टॉफ, आदेश की एकता, सोपान, नियंत्रण का क्षेत्र
- केन्द्रीकरण और विकेन्द्रीकरण, संगठन के प्रकार–औपचारिक एवं अनौपचारिक, संगठन के प्रारूप, विभाग, सार्वजनिक निगम और परिषद् ।
- मुख्य कार्यपालक : प्रकार, कार्य और भूमिका ।

इकाई–6

- कार्मिक प्रशासन : भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति, अनुशासन, मनोबल, नियोक्ता–कर्मचारी सम्बन्ध ।
- नौकरशाही : सिद्धान्त, प्रकार तथा भूमिका, मैक्स वेबर और उनके आलोचक, लोक सेवक–मंत्रि सम्बन्ध ।
- नेतृत्व, निर्णय प्रक्रिया में इसकी भूमिका, संचार, भारत में विकास योजना और प्रशासन, नौकरशाही और विकास की चुनौतियाँ, उदारीकरण का लोक प्रशासन पर प्रभाव ।
- वित्तीय प्रशासन : बजट, लेखा परीक्षा।
- सुशासन, प्रशासनिक भ्रष्टाचार की समस्याएँ, पारदर्शिता, जवाबदेही और सूचना का अधिकार । शिकायत निवारण संस्थाएँ : ऑम्बुडसमेन, लोकपाल और लोकायुक्त ।

इकाई–7

- अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धो के अध्ययन के विभिन्न सिद्धान्त और उपागम: आदर्शवादी, यथार्थवादी, व्यवस्था, खेल, संचार और निर्णय–निर्माण।
- अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में शक्ति हित और विचारधार, शक्ति के तत्व, अधिग्रहण। शक्ति का उपयोग और सीमाएँ, अवधारणा, राष्ट्रीय हित का निर्माण और उन्नयन, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की विचाराधारा का अर्थ, भूमिका और प्रासंगिकता।
- शस्त्र और युद्ध : जातीय संघर्षों सहित युद्धों/संघर्षों की प्रकृति, कारण और प्रकार पारम्परिक, नाभिकीय/जैव रासायनिक युद्ध, पराधन, शस्त्र स्पर्धा, शस्त्र नियंत्रण, निरस्तीकरण विवादों का शांतिपूर्ण समाधान कूटनीति।
- शीत युद्ध, गठबंधन, गुटनिरपेक्षता, शीत युद्ध का अन्त, वैश्वीकरण ।
- अन्तर्राष्ट्रीय कानून में राज्यों के अधिकार और कर्तव्य, हस्तक्षेप, संधि–विधि। युद्धों पर रोक और उन्मूलन समाप्ति।

इकाई–8

- अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का राजनीतिक अर्थशास्त्र, नव अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, उत्तर–दक्षिण संवाद, दक्षिण–दक्षिण सहयोग, विश्व व्यापार संगठन, नव–उपनिवेशवाद और निर्भरता ।
- क्षेत्रीय और उप–क्षेत्रीय संगठन विशेषतः सार्क, आसियान, ओपेक, ओ.ए.एस. एवं जी – 20।
- संयुक्त राष्ट्र संघ– उद्देश्य, लक्ष्य, संरचना और कार्य प्रणाली का मूल्यांकन, शांति और विकास दृष्टिकोण, चार्टर संशोधन, संयुक्त राष्ट्र संघ में शक्ति संघर्ष एवं राजनीति, वित्तीय प्रबन्ध और शांति स्थापना अभियान ।
- अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में भारत की भूमिका : भारत के पड़ोसी देशों से संबंध, युद्ध, सुरक्षा सम्बन्धी सरोकार, मध्यस्थ की भूमिका ।
- भारतीय विदेश नीति की विलक्षण विशेषताएँ और राजनय ।

इकाई–9

- राज्यों का पुनर्गठन (1956) तथा मध्यप्रदेश का निर्माण। मध्यप्रदेश का विभाजन (2000), मध्यप्रदेश की राजनीति के निर्धारक तत्व और विशेषताएँ ।
- राज्यपाल– नियुक्ति, शक्ति, स्थिति, मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद् : संगठन, कार्य एवं भूमिका।
- मध्यप्रदेश की विधानसभाः संगठन एवं शक्तियाँ, अध्यक्ष की भूमिका, विपक्ष की भूमिका।
- मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, संगठन, क्षेत्राधिकार एवं भूमिका ।
- मध्यप्रदेश की दलीय व्यवस्था एवं मुख्य राजनीतिक दल, मध्यप्रदेश में चुनाव राजनीति और मतदान व्यवहार ।

Downloaded from www.pdf.tube

इकाई–10

- मध्यप्रदेश का प्रशासन : सचिवालय, मुख्यसचिव, सचिव तथा आयुक्त, मध्यप्रदेश में जिला प्रशासन, जिलाधीश की भूमिका ।
- मध्यप्रदेश में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन : संगठन एवं शक्तियाँ, शहरी स्थानीय स्वशासन : संगठन एवं शक्तियां, स्थानीय स्वशासन में वित्त, नौकरशाही एवं स्वायत्ता का महत्व ।
- मध्यप्रदेश का राजनीतिक परिदृश्य : जनजातीय, पिछड़े एवं वंचित वर्ग का उत्थान एवं नक्सली समस्या से जुड़े मुद्दे।
- मध्यप्रदेश की राजनीति में महिलाओं का योगदान ।
- मध्यप्रदेश में विकास की राजनीति ।

****

NODIA

अध्याय 01
राजनीतिक चिंतन एवं विचारक

1. कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार, एक राजा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?
(A) व्यक्तिगत मोक्ष की प्राप्ति
(B) प्रजा का कल्याण और सुख
(C) किसी भी साधन से साम्राज्य का विस्तार
(D) धार्मिक अनुष्ठानों का कड़ाई से पालन

2. निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्लेटो के 'दार्शनिक राजा' की अवधारणा का सबसे अच्छा वर्णन करता है?
(A) एक शासक जिसके पास 'शुभ के स्वरूप' का सच्चा ज्ञान है और वह उसी के अनुसार शासन करता है।
(B) एक शासक जो शाही वंश के माध्यम से सत्ता प्राप्त करता है और दर्शन को एक शौक के रूप में पढ़ता है।
(C) लोकप्रिय मत द्वारा चुना गया एक शासक जो दार्शनिक आदर्शों को लागू करने का वचन देता है।
(D) एक लोकतांत्रिक नेता जो हर निर्णय के लिए दार्शनिकों की परिषद से परामर्श करता है।

3. महात्मा गांधी के लिए, 'स्वराज' की अवधारणा मुख्य रूप से किसका प्रतीक है?
(A) केवल ब्रिटिश शासन से राजनीतिक स्वतंत्रता।
(B) एक समाजवादी अर्थव्यवस्था की स्थापना।
(C) स्व का शासन और आत्म-नियंत्रण।
(D) धर्म और राजनीति का पूर्ण पृथक्करण।

4. अरस्तू के संविधानों के वर्गीकरण के संबंध में गलत कथन की पहचान करें।
(A) राजतंत्र सामान्य हित के लिए एक व्यक्ति का शासन है।
(B) कुलीनतंत्र सामान्य हित के लिए कुछ लोगों का शासन है।
(C) पॉलिटी सामान्य हित के लिए बहुतों का शासन है।
(D) लोकतंत्र पॉलिटी का विकृत रूप है, जो सभी के हितों की पूर्ति करता है।

5. मैकियावेली ने 'द प्रिंस' में शासक को किन दो जानवरों की तरह बनने की सलाह दी है?
(A) शेर और बाज
(B) भेड़िया और भेड़
(C) शेर और लोमड़ी
(D) भालू और सांप

6. निम्नलिखित में से कौन सा कौटिल्य के राज्य के 'सप्तांग' सिद्धांत का तत्व नहीं है?
(A) स्वामी (राजा)
(B) धर्म
(C) अमात्य (मंत्री)
(D) कोष

7. सूची I के विचारकों का सूची II की अवधारणाओं से मिलान करें।
सूची I:
P. एम.एन. रॉय
Q. जय प्रकाश नारायण
R. अरविंदो घोष
S. बी.आर. अंबेडकर।
सूची II:
1. आध्यात्मिक राष्ट्रवाद
2. जाति का विनाश
3. रेडिकल ह्युमनिज्म
4. सम्पूर्ण क्रांति।
(A) P-3, Q-4, R-1, S-2
(B) P-1, Q-2, R-3, S-4
(C) P-3, Q-1, R-4, S-2
(D) P-4, Q-3, R-2, S-1

8. थॉमस हॉब्स ने अपनी किस प्रसिद्ध कृति में प्राकृतिक अवस्था को "हर व्यक्ति का हर व्यक्ति के विरुद्ध युद्ध" के रूप में वर्णित किया है?
(A) लेविआथन
(B) टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट
(C) द सोशल कॉन्ट्रैक्ट
(D) डी सिवे

9. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिन्हें कथन I और कथन II के रूप में अंकित किया गया है।
कथन I: जॉन लॉक को अक्सर आधुनिक उदारवाद का जनक माना जाता है।
कथन II: लॉक ने एक ही शासक में निहित पूर्ण और अविभाज्य संप्रभुता की वकालत की। उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
(D) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।

Click Here to Buy book on Amazon

10. निम्नलिखित विचारकों में से किसने गांधी द्वारा 'सत्याग्रह' के रूप में लोकप्रिय बनाने से पहले एक राजनीतिक उपकरण के रूप में 'निष्क्रिय प्रतिरोध' की अवधारणा की वकालत की थी?
(A) अरविंदो घोष
(B) एम.एन. रॉय
(C) बी.आर. अंबेडकर
(D) सावरकर

11. अभिकथन (A): प्लेटो के लिए, राज्य में न्याय तब प्राप्त होता है जब प्रत्येक वर्ग दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप किए बिना अपना निर्दिष्ट कार्य करता है।
कारण (R): प्लेटो एक आदर्श समाज की आधारशिला के रूप में श्रम के सख्त विभाजन और कार्यात्मक विशेषज्ञता में विश्वास करते थे।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

12. वैध राजनीतिक अधिकार के आधार के रूप में 'सामान्य इच्छा' की अवधारणा को किसके द्वारा सबसे प्रभावशाली ढंग से व्यक्त किया गया था?
(A) थॉमस हॉब्स
(B) ज्यां-जैक रूसो
(C) जॉन लॉक
(D) जेरेमी बेंथम

13. महाभारत के शांति पर्व के अनुसार, 'राजधर्म' का तात्पर्य है:
(A) राजा के विरुद्ध विद्रोह करने का नागरिकों का अधिकार।
(B) राजा की शक्ति की दैवीय उत्पत्ति।
(C) राजा के कर्तव्य और दायित्व।
(D) नए राजा को चुनने की प्रक्रिया।

14. डॉ. बी.आर. अंबेडकर के विचारों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. वे जाति व्यवस्था के प्रखर आलोचक थे और इसके पूर्ण विनाश की वकालत करते थे।
2. उनका मानना था कि सामाजिक सुधार की तुलना में राजनीतिक स्वतंत्रता अधिक महत्वपूर्ण थी।
3. उन्होंने भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2, और 3

15. जेरेमी बेंथम के उपयोगितावाद का केंद्रीय सिद्धांत क्या है?
(A) अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख।
(B) अक्षुण्ण प्राकृतिक अधिकारों की सुरक्षा।
(C) समुदाय की सामान्य इच्छा की प्राप्ति।
(D) 'परम विचार' का ऐतिहासिक विकास।

16. जे.एस. मिल का 'हानि सिद्धांत', जैसा कि "ऑन लिबर्टी" में व्यक्त किया गया है, क्या सुझाव देता है?
(A) वे सभी कार्य जो हानि पहुँचाते हैं, चाहे स्वयं को या दूसरों को, प्रतिबंधित होने चाहिए।
(B) राज्य किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता में केवल दूसरों को हानि से बचाने के लिए हस्तक्षेप कर सकता है।
(C) राज्य को उन कार्यों को बढ़ावा देना चाहिए जो बाहरी शत्रुओं को सामूहिक हानि पहुँचाते हैं।
(D) व्यक्ति कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हैं, भले ही इससे दूसरों को नुकसान हो, बशर्ते वे सहमत हों।

17. कौटिल्य के 'मंडल' सिद्धांत में, 'अरि' है:
(A) विजिगीषु राज्य का प्राकृतिक सहयोगी।
(B) पड़ोसी राज्य जो स्वाभाविक शत्रु है।
(C) दो प्रतिद्वंद्वियों के बीच स्थित तटस्थ राज्य।
(D) विजिगीषु राज्य के पीछे स्थित राज्य।

18. हेगेल का प्रसिद्ध कथन, "जो वास्तविक है वह तर्कसंगत है और जो तर्कसंगत है वह वास्तविक है," का तात्पर्य है कि:
(A) विश्व का ऐतिहासिक विकास एक तार्किक और समझने योग्य स्वरूप का अनुसरण करता है।
(B) सभी मौजूदा राजनीतिक संस्थाएं स्वाभाविक रूप से पूर्ण हैं और आलोचना से परे हैं।
(C) मानवीय तर्क उस वास्तविकता का निर्माण करता है जिसका कोई स्वतंत्र वस्तुनिष्ठ अस्तित्व नहीं है।
(D) केवल अमूर्त विचार ही वास्तविक हैं जबकि भौतिक दुनिया एक पूर्ण भ्रम है।

19. निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत सुमेलित है?
(A) प्लेटो - द रिपब्लिक
(B) अरस्तू - पॉलिटिक्स
(C) मैकियावेली - द सोशल कॉन्ट्रैक्ट
(D) हॉब्स - लेविआथन

20. निम्नलिखित विचारकों को उनके जन्म के सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें:
1. थॉमस हॉब्स
2. निकोलो मैकियावेली
3. जॉन लॉक
4. ज्यां-जैक रूसो।
(A) 2, 1, 3, 4
(B) 1, 2, 3, 4
(C) 2, 3, 1, 4
(D) 3, 4, 2, 1

21. कार्ल मार्क्स का 'अलगाव' का सिद्धांत किसे संदर्भित करता है?

Downloaded from www.pdf.tube

(A) लोकतंत्र में नागरिकों द्वारा अनुभव की जाने वाली राजनीतिक शक्तिहीनता की भावना।
(B) औद्योगिकीकरण के कारण जनसंख्या का भौगोलिक विस्थापन।
(C) श्रमिकों का उनके उत्पादों, स्वयं से और अन्य लोगों से अलगाव।
(D) बुर्जुआ वर्ग द्वारा पारंपरिक धार्मिक और नैतिक मूल्यों की अस्वीकृति।

22. 'सकारात्मक स्वतंत्रता' की अवधारणा किस विचारक के साथ सबसे निकटता से जुड़ी हुई है?
(A) जॉन लॉक
(B) टी.एच. ग्रीन
(C) जे.एस. मिल
(D) थॉमस हॉब्स

23. लेनिन का साम्राज्यवाद का सिद्धांत तर्क देता है कि साम्राज्यवाद है:
(A) पिछड़े राष्ट्रों को सभ्य बनाने का एक नैतिक मिशन।
(B) आक्रामक राष्ट्रीय नेताओं द्वारा लिया गया एक राजनीतिक विकल्प।
(C) एक अस्थायी चरण जिसे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से सुधारा जा सकता है।
(D) एकाधिकार पूंजीवाद के लिए एक अनिवार्य आर्थिक आवश्यकता।

24. अभिकथन (A): एम.एन. रॉय ने अपने बाद के चरण में 'रेडिकल ह्युमनिज्म' और दलविहीन लोकतंत्र की वकालत की।
कारण (R): वे बुर्जुआ लोकतंत्र और कम्युनिस्ट तानाशाही दोनों से निराश हो गए थे और तर्कसंगत, नैतिक व्यक्ति पर केंद्रित एक तीसरे मार्ग की तलाश कर रहे थे।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

25. माओ जेदोंग के 'अंतर्विरोध' के सिद्धांत को सबसे अच्छी तरह से किस रुप में समझा जा सकता है?
(A) कन्फ्यूशियस सद्भाव के पक्ष में मार्क्सवादी द्वंद्ववाद की अस्वीकृति।
(B) अपने विरोधियों के बीच संघर्ष पैदा करने की एक राजनीतिक रणनीति।
(C) यह विचार कि एक मुख्य अंतर्विरोध किसी प्रक्रिया की प्रकृति को निर्धारित करता है।
(D) यह विश्वास कि सभी अंतर्विरोध समान हैं और उन्हें एक साथ हल किया जाना चाहिए।

26. एंटोनियो ग्राम्शी की 'हेजेमनी' की अवधारणा का तात्पर्य है:
(A) एक शासक वर्ग का नेतृत्व जो जनता की सहमति प्राप्त करता है।
(B) पुलिस और सेना के माध्यम से राज्य का प्रत्यक्ष और दमनकारी शासन।
(C) वैश्विक व्यापार के माध्यम से एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्रों पर आर्थिक प्रभुत्व।
(D) सर्वहारा वर्ग द्वारा पूंजीवादी राज्य का क्रांतिकारी तख्तापलट।

27. सूची I की पुस्तकों का सूची II के लेखकों के साथ मिलान करें।
सूची I:
P. ए थ्योरी ऑफ जस्टिस
Q. एनार्की, स्टेट, एंड यूटोपिया
R. ऑन लिबर्टी
S. द प्रिंस।
सूची II:
1. जे.एस. मिल
2. निकोलो मैकियावेली
3. जॉन रॉल्स
4. रॉबर्ट नोजिक।
(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-3, Q-4, R-1, S-2
(C) P-3, Q-1, R-4, S-2
(D) P-4, Q-3, R-2, S-1

28. जॉन रॉल्स की 'मूल स्थिति' में, 'अज्ञानता का पर्दा' कार्य करता है:
(A) व्यक्तियों को उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति के आधार पर बातचीत करने की अनुमति देना।
(B) समाज में किसी के स्थान या प्राकृतिक क्षमताओं के ज्ञान को रोकना।
(C) यह सुनिश्चित करना कि न्याय के सिद्धांत समाज के सबसे प्रतिभाशाली सदस्यों का पक्ष लें।
(D) अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के उपयोगितावादी सिद्धांत को बढ़ावा देना।

29. रॉबर्ट नोजिक के 'न्याय के हकदारी सिद्धांत' में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत शामिल नहीं है?
(A) अधिग्रहण में न्याय का सिद्धांत।
(B) हस्तांतरण में न्याय का सिद्धांत।
(C) स्वरूपित वितरण का सिद्धांत।
(D) अन्याय के सुधार का सिद्धांत।

30. समुदायवादी विचार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. यह 'असंलग्न स्व' की उदारवादी अवधारणा की आलोचना करता है।
2. यह व्यक्तिगत पहचान को आकार देने में समुदाय और साझा मूल्यों के महत्व पर बल देता है।
3. यह सार्वभौमिक रुप से एक न्यूनतम, गैर-हस्तक्षेपवादी राज्य का समर्थन करता है।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

NODIA

(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2, और 3

31. शांति पर्व के अनुसार, राज्य और राजपद की उत्पत्ति कैसे हुई?
(A) यह अराजकता की स्थिति से बचने के लिए लोगों के बीच एक सामाजिक अनुबंध से उत्पन्न हुआ।
(B) यह पापियों को दंडित करने के लिए ईश्वर की प्रत्यक्ष रचना थी।
(C) इसे सबसे शक्तिशाली योद्धा द्वारा विजय के माध्यम से स्थापित किया गया था।
(D) यह परिवार और गाँव से स्वाभाविक रूप से विकसित हुआ।

32. 'सम्पूर्ण क्रांति' की अवधारणा किस भारतीय विचारक से जुड़ी है?
(A) एम.एन. रॉय
(B) जय प्रकाश नारायण
(C) महात्मा गांधी
(D) बी.आर. अंबेडकर

33. वी.डी. सावरकर की कृति "एसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व" में मुख्य विषय क्या है?
(A) एक धर्मनिरपेक्ष, बहु-धार्मिक भारतीय राज्य को बढ़ावा देना।
(B) यह विचार कि एक हिंदू भारत को अपनी पितृभूमि और पुण्यभूमि दोनों मानता है।
(C) आधुनिक तकनीक को त्यागने और वैदिक जीवन की ओर लौटने का आह्वान।
(D) कम्युनिस्ट आर्थिक मॉडल को अपनाने का तर्क।

34. अरस्तू के 'स्वर्णिम मध्य' के विचार को उनके राजनीतिक सिद्धांत में किसके प्रति प्राथमिकता में लागू किया गया है?
(A) पॉलिटी, क्योंकि यह अल्पतंत्र और लोकतंत्र को संतुलित करने वाला एक मिश्रित संविधान है।
(B) राजतंत्र, क्योंकि यह निरंकुशता और अराजकता के चरम से बचता है।
(C) निरंकुश शासन, क्योंकि यह सरकार का सबसे कुशल रूप है।
(D) शुद्ध लोकतंत्र, क्योंकि यह सभी नागरिकों को समान रूप से शक्ति देता है।

35. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिन्हें कथन I और कथन II के रूप में अंकित किया गया है।
कथन I: रूसो ने तर्क दिया कि निजी संपत्ति की संस्था असमानता और सामाजिक बुराइयों का प्राथमिक स्रोत थी।
कथन II: रूसो का मानना था कि प्रकृति की आदिम अवस्था में लौटना एक व्यवहार्य और वांछनीय राजनीतिक लक्ष्य था।
उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
(D) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।

36. जे.एस. मिल के अनुसार, निम्नलिखित में से कौन सा किसी राय को दबाने का वैध कारण नहीं है?
(A) क्योंकि बहुमत द्वारा इसे गलत माना जाता है।
(B) क्योंकि प्रचलित सामाजिक मानकों द्वारा इसे अनैतिक माना जाता है।
(C) क्योंकि यह सत्तासीन सरकार के लिए अपमानजनक है।
(D) क्योंकि यह सीधे तौर पर किसी विशिष्ट व्यक्ति के विरुद्ध हिंसा के कार्य को उकसाता है।

37. अभिकथन (A): कार्ल मार्क्स ने तर्क दिया कि पूंजीवादी समाज में राज्य बुर्जुआ वर्ग का एक साधन है।
कारण (R): राज्य पूरे बुर्जुआ वर्ग के सामान्य मामलों का प्रबंधन करने और सर्वहारा वर्ग को दबाने का काम करता है।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

38. 'न्यूनतम राज्य' या 'नाइट-वॉचमैन स्टेट' की अवधारणा किसके राजनीतिक दर्शन की आधारशिला है?
(A) जॉन रॉल्स
(B) रॉबर्ट नोज़िक
(C) टी.एच. ग्रीन
(D) एंटोनियो ग्राम्शी

39. गांधीवादी विचार में, 'सर्वोदय' का अर्थ है:
(A) बहुमत का शासन।
(B) केवल दलितों का उत्थान।
(C) हिंसा के माध्यम से वर्गहीन समाज की स्थापना।
(D) सभी का कल्याण।

40. वेंगार्ड पार्टी के भीतर लेनिन के 'लोकतांत्रिक केंद्रीयवाद' के सिद्धांत का तात्पर्य है:
(A) चर्चा की पूर्ण स्वतंत्रता, लेकिन कार्रवाई की पूर्ण एकता।
(B) समाजवादी राज्य के भीतर एक बहु-दलीय व्यवस्था।
(C) प्रत्यक्ष लोकतंत्र जहाँ सभी निर्णय लोकप्रिय मत द्वारा लिए जाते हैं।
(D) केंद्रीय समिति के निर्णयों की पुष्टि क्षेत्रीय परिषदों द्वारा की जानी चाहिए।

41. निम्नलिखित में से कौन प्लेटो की 'गुफा का रूपक' का सबसे अच्छा वर्णन करता है?
(A) जनता को उनके अपने भले के लिए धोखा देने की एक राजनीतिक रणनीति।
(B) एक नगर-राज्य के लिए आदर्श वास्तुशिल्प संरचना का विवरण।

Click Here to Buy book on Amazon

(C) अज्ञानता से ज्ञान के प्रकाश तक की यात्रा को दर्शाने वाली एक कहानी।
(D) शासकों के बीच निजी संपत्ति के उन्मूलन के लिए एक तर्क।

42. ग्राम्शी की 'स्थिति का युद्ध' की अवधारणा किन समाजों के लिए सबसे उपयुक्त है?
(A) एक मजबूत और जटिल नागरिक समाज वाले समाज।
(B) एक कमजोर और अविकसित नागरिक समाज वाले समाज।
(C) एक तानाशाही सैन्य शासन।
(D) एक पूर्व-पूंजीवादी सामंती संरचना।

43. जॉन लॉक द्वारा बताए गए उन तीन प्राकृतिक अधिकारों में से कौन सा नहीं है जिन्हें सरकार द्वारा संरक्षित किया जाना चाहिए?
(A) जीवन
(B) स्वतंत्रता
(C) संपत्ति
(D) सुख

44. निम्नलिखित कृतियों को उनके प्रकाशन के कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें:
1. ए थ्योरी ऑफ जस्टिस
2. एनार्की, स्टेट, एंड यूटोपिया
3. ऑन लिबर्टी
4. कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो
(A) 4, 3, 1, 2
(B) 3, 4, 1, 2
(C) 4, 3, 2, 1
(D) 3, 1, 4, 2

45. 'शांति पर्व' किस प्राचीन भारतीय महाकाव्य का हिस्सा है?
(A) रामायण
(B) अर्थशास्त्र
(C) महाभारत
(D) मनुस्मृति

46. "मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ था, और वह हर जगह जंजीरों में है।" यह प्रसिद्ध पंक्ति रूसो की किस पुस्तक से है?
(A) एमाइल
(B) डिस्कोर्स ऑन इनइक्वलिटी
(C) कन्फेशंस
(D) द सोशल कॉन्ट्रैक्ट

47. अंबेडकर के अनुसार, 'एक व्यक्ति, एक मूल्य' का सिद्धांत क्या प्राप्त करने के लिए केंद्रीय है?
(A) सामाजिक लोकतंत्र
(B) आर्थिक समानता
(C) राजनीतिक केंद्रीकरण
(D) धार्मिक अनुरूपता

48. सूची I के विचारकों का सूची II के विचारों के साथ मिलान करें।
सूची I:
P. हेगेल
Q. टी.एच. ग्रीन
R. ग्राम्शी
S. एम.एन. रॉय
सूची II:
1. सकारात्मक स्वतंत्रता
2. राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है
3. नव मानवतावाद
4. हेजेमनी
(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-2, Q-1, R-4, S-3
(C) P-2, Q-4, R-1, S-3
(D) P-3, Q-1, R-4, S-2

49. कौटिल्य के अनुसार, वे 'चार विद्याएँ' कौन सी हैं जिनमें एक राजा को निपुण होना चाहिए?
(A) धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष
(B) आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंडनीति
(C) सैन्य रणनीति, अर्थशास्त्र, कानून और धर्म
(D) तर्कशास्त्र, तत्वमीमांसा, नैतिकता और राजनीति

50. हॉब्स के सामाजिक अनुबंध के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. यह लोगों और संप्रभु के बीच एक अनुबंध है।
2. लोग आत्म-संरक्षण के अधिकार सहित अपने सभी अधिकार छोड़ देते हैं।
3. अनुबंध द्वारा बनाया गया संप्रभु इसका पक्षकार नहीं है।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल 3
(B) केवल 1 और 2
(C) केवल 1 और 3
(D) केवल 2 और 3

51. जे.एस. मिल ने बेंथम के उपयोगितावाद में क्या महत्वपूर्ण संशोधन किया?
(A) उपयोगिता के सिद्धांत को पूरी तरह से खारिज कर दिया।
(B) तर्क दिया कि केवल शासक वर्ग का सुख मायने रखता है।
(C) उच्च और निम्न सुखों के बीच एक गुणात्मक अंतर प्रस्तुत किया।
(D) इस बात से इनकार किया कि दुख और सुख मानव जाति के दो संप्रभु स्वामी हैं।

52. माओवादी सिद्धांत में, एक अर्ध-सामंती देश में क्रांति की रणनीति क्या थी?
(A) सभी प्रमुख राष्ट्रीय शहरों में शहरी सर्वहारा विद्रोह आयोजित करना।

NODIA

(B) तेजी से तख्तापलट के माध्यम से सत्ता हथियाने के लिए एक अग्रगामी दल पर भरोसा करना।
(C) कानूनी साधनों के माध्यम से समाजवाद की ओर शांतिपूर्ण संक्रमण की तलाश करना।
(D) ग्रामीण क्षेत्रों पर आधारित एक दीर्घकालिक जनयुद्ध छेड़ना।

53. जॉन रॉल्स के समुदायवादी आलोचकों का तर्क है कि उनकी 'मूल स्थिति' त्रुटिपूर्ण है क्योंकि:
(A) यह परंपरा और सामुदायिक मानदंडों को बहुत अधिक महत्व देती है।
(B) यह एक ऐसे न्यूनतम राज्य की ओर ले जाती है जो सामान्य हित के लिए साधन प्रदान नहीं कर सकता।
(C) यह एक असामाजिक स्व की पूर्वकल्पना करती है, जो अपने समुदाय से अलग है।
(D) यह अधिकतम सुख की उपयोगितावादी गणना पर आधारित है।

54. आर्थिक मॉडल के रूप में 'ट्रस्टीशिप' की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी?
(A) बी.आर. अंबेडकर
(B) एम.के. गांधी
(C) एम.एन. रॉय
(D) जय प्रकाश नारायण

55. अभिकथन (A): अरस्तू को दासता का समर्थक माना जाता है।
कारण (R): उनका मानना था कि कुछ लोग स्वभाव से दास होते हैं, जिनमें स्व-शासन के लिए तर्कसंगत क्षमता का अभाव होता है, और दासता स्वामी तथा प्राकृतिक दास दोनों के लिए हितकारी है।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

56. निम्नलिखित में से किसे छोड़कर सभी को 'समुदायवादी' विचारक माना जाता है?
(A) रॉबर्ट नोजिक
(B) माइकल सैंडेल
(C) चार्ल्स टेलर
(D) माइकल वाल्ज़र

57. जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत में 'भेद का सिद्धांत' क्या बताता है?
(A) सभी सामाजिक और आर्थिक असमानताएं स्वाभाविक रूप से अन्यायपूर्ण हैं।
(B) प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक और आर्थिक वस्तुओं के समान हिस्से का अधिकार है।
(C) असमानताएं समाज के सबसे कम सुविधा प्राप्त सदस्यों के लिए हितकारी होनी चाहिए।
(D) राज्य को निजी संपत्ति के वितरण में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

58. आत्मा के तीन भागों का प्लेटो का सिद्धांत, जो राज्य के तीन वर्गों के अनुरूप है, किन तत्वों से बना है?
(A) विवेक, साहस और तृष्णा
(B) इड, ईगो और सुपरईगो
(C) शरीर, मन और आत्मा
(D) संवेदना, धारणा और संज्ञान

59. कौटिल्य के विचार में 'दंडनीति' मुख्य रूप से किसका प्रतीक है?
(A) कूटनीति और विदेश नीति की कला।
(B) धार्मिक और नैतिक आचरण की संहिता।
(C) दीवानी और फौजदारी कानून की प्रणाली।
(D) शासन या लोक प्रशासन का विज्ञान।

60. निम्नलिखित में से किस विचारक ने हेगेल के द्वंद्ववाद को "सिर के बल खड़ा" बताया और इसे "फिर से पैरों के बल" खड़ा करने का प्रयास किया?
(A) टी.एच. ग्रीन
(B) कार्ल मार्क्स
(C) जे.एस. मिल
(D) एंटोनियो ग्राम्शी

61. एम.एन. रॉय का 'रेडिकल ह्युमनिज्म' का दर्शन किस केंद्रीय मूल्य पर आधारित है?
(A) राष्ट्र
(B) सर्वहारा वर्ग
(C) व्यक्तिगत मानव
(D) आध्यात्मिक क्षेत्र

62. मैकियावेली के राजनीतिक विचार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
(A) उन्होंने राजनीति को पारंपरिक नैतिकता और धर्म से पृथक किया।
(B) उन्होंने तर्क दिया कि एक शासक को राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अनैतिक साधनों का उपयोग करने के लिए तैयार रहना चाहिए।
(C) उन्होंने राजनीति में 'वीरता' और 'भाग्य' दोनों की भूमिका पर बल दिया।
(D) उनका मानना था कि सरकार का गणतंत्रवादी रूप स्वाभाविक रूप से अस्थिर और अवांछनीय है।

63. रूसो की 'सामान्य इच्छा' की अवधारणा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. यह केवल नागरिकों की सभी विशेष इच्छाओं का योग है।
2. इसका लक्ष्य हमेशा सामान्य हित होता है।
3. एक बड़े गणराज्य में निर्वाचित अधिकारियों द्वारा इसका प्रतिनिधित्व किया जा सकता है।

Downloaded from www.pdf.tube

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल 1 और 3
(B) केवल 2
(C) केवल 2 और 3
(D) 1, 2, और 3

64. टी.एच. ग्रीन के लिए, राज्य का अंतिम कार्य क्या है?
(A) पूंजीवादी उद्यम के माध्यम से राष्ट्र की संपत्ति को अधिकतम करना।
(B) नैतिक विकास और आत्म-साक्षात्कार के मार्ग की बाधाओं को दूर करना।
(C) व्यक्तिगत जीवन में न्यूनतम हस्तक्षेप के साथ कानून और व्यवस्था बनाए रखना।
(D) स्वयं राज्य के अंततः विलुप्त होने की तैयारी करना।

65. मार्क्सवादी विचार के केंद्र में 'ऐतिहासिक भौतिकवाद' शब्द का अर्थ है कि:
(A) इतिहास शक्तिशाली व्यक्तियों के महान कार्यों का एक विवरण है।
(B) समाज का भौतिक या आर्थिक आधार उसके राजनीतिक और वैचारिक अधिरचना को निर्धारित करता है।
(C) मनुष्य केवल भौतिक संपत्ति की खोज से प्रेरित होते हैं।
(D) इतिहास का लक्ष्य पूर्ण भौतिक प्रचुरता की स्थिति प्राप्त करना है।

66. गांधीवादी शब्दावली में, 'सत्याग्रही' वह है जो:
(A) अन्याय का विरोध करने में सत्य और अहिंसा का पालन करता है।
(B) न्याय पाने के लिए अंतिम उपाय के रूप में हिंसा का उपयोग करता है।
(C) चुनावी साधनों के माध्यम से राजनीतिक शक्ति चाहता है।
(D) व्यक्तिगत ज्ञान की खोज के लिए समाज से पृथक हो जाता है।

67. निम्नलिखित विचारकों को उनके प्रमुख राजनीतिक लेखों के कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें:
1. प्लेटो
2. कौटिल्य
3. अरस्तू
4. शांति पर्व।
(A) 4, 1, 3, 2
(B) 1, 3, 4, 2
(C) 4, 2, 1, 3
(D) 2, 4, 1, 3

68. अरविंदो घोष के राजनीतिक विचार उग्र राष्ट्रवाद के समर्थक से विकसित होकर किसके प्रस्तावक बन गए?
(A) ब्रिटिश ढांचे के भीतर संवैधानिक आंदोलन।
(B) एक हिंसक अंतर्राष्ट्रीय सर्वहारा क्रांति।
(C) दलविहीन लोकतंत्र और विकेंद्रीकरण।
(D) आध्यात्मिक विकास और मानव जीवन का दैवीकरण।

69. अरस्तू के अनुसार, एक राजा और एक निरंकुश शासक के बीच मुख्य अंतर यह है कि:
(A) राजा लोगों की सहमति से शासन करता है, जबकि निरंकुश शासक नहीं।
(B) राजा को अपना पद विरासत में मिलता है, जबकि निरंकुश शासक सत्ता छीन लेता है।
(C) राजा सामान्य हित के लिए शासन करता है, जबकि निरंकुश शासक अपने लाभ के लिए शासन करता है।
(D) राजा कानून से बंधा होता है, जबकि निरंकुश शासक कानून से ऊपर होता है।

70. सूची I की अवधारणाओं का सूची II के संबंधित विचारकों के साथ मिलान करें।
सूची I:
P. हानि सिद्धांत
Q. अज्ञानता का पर्दा
R. सर्वहारा वर्ग की तानाशाही
S. वीर कौशल और भाग्य
सूची II:
1. जॉन रॉल्स
2. कार्ल मार्क्स
3. निकोलो मैकियावेली
4. जे.एस. मिल।
(A) P-4, Q-1, R-2, S-3
(B) P-1, Q-4, R-2, S-3
(C) P-4, Q-2, R-1, S-3
(D) P-3, Q-1, R-4, S-2

71. जय प्रकाश नारायण की 'सम्पूर्ण क्रांति' का लक्ष्य किन क्षेत्रों में परिवर्तन करना था?
(A) केवल राजनीतिक और आर्थिक
(B) केवल सैन्य और प्रशासनिक
(C) केवल धार्मिक और आध्यात्मिक
(D) सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, वैचारिक और आध्यात्मिक

72. प्लेटो के आदर्श राज्य में 'संरक्षकों' की क्या भूमिका है?
(A) ज्ञान और न्याय पर ध्यान केंद्रित करते हुए राज्य पर शासन करना।
(B) राज्य की भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कृषि और व्यापार में संलग्न होना।
(C) बाहरी खतरों से राज्य की रक्षा करना और आंतरिक व्यवस्था बनाए रखना।
(D) कला और कविता सृजित करना जो 'शुभ के स्वरूप' को दर्शाती हो।

73. 'एनीहिलेशन ऑफ कास्ट' किसके द्वारा तैयार किए गए प्रसिद्ध भाषण का शीर्षक है?
(A) एम.के. गांधी

NODIA

(B) एम.एन. रॉय
(C) बी.आर. अंबेडकर
(D) वी.डी. सावरकर

74. अभिकथन (A): जॉन लॉक का सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत सीमित सरकार का औचित्य प्रदान करता है।
कारण (R): लॉक के लिए, लोग एक ऐसी सरकार बनाने के लिए अनुबंध करते हैं जो उनके जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के पूर्व-विद्यमान प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करती है, और यदि सरकार इस विश्वास का उल्लंघन करती है तो उनके पास विद्रोह का अधिकार सुरक्षित रहता है।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

75. जेरेमी बेंथम का 'फेलिसिफिक कैलकुलस' एक ऐसी विधि थी जिसे किस लिए बनाया गया था?
(A) विभिन्न आय स्तरों के लिए सही कर दर निर्धारित करना।
(B) जनसंख्या के आधार पर संसदीय सीटें आवंटित करना।
(C) इतिहास में 'परम आत्मा' की प्रगति को मापना।
(D) किसी कार्य के परिणामस्वरूप होने वाले सुख या दुख की मात्रा की गणना करना।

76. हेगेल के राजनीतिक दर्शन को सबसे अच्छी तरह से किस रूप में वर्णित किया जा सकता है?
(A) उदारवादी व्यक्तिवाद
(B) आदर्शवादी और रूढ़िवादी
(C) अराजकतावाद
(D) अनुभवजन्य और उपयोगितावादी

77. "जहाँ कानून नहीं है, वहाँ स्वतंत्रता नहीं है।" यह कथन किसके द्वारा दिया गया था?
(A) थॉमस हॉब्स
(B) कार्ल मार्क्स
(C) जॉन लॉक
(D) रॉबर्ट नोजिक

78. कौटिल्य की विदेश नीति में छह-चरणीय नीति में निम्नलिखित में से किसे छोड़कर सभी शामिल हैं?
(A) संधि
(B) विग्रह
(C) आसन
(D) धर्म

79. राज्य के बारे में ग्राम्शी का दृष्टिकोण पारंपरिक मार्क्सवादी दृष्टिकोण से किस प्रकार भिन्न है?
(A) ग्राम्शी ने राज्य को बल प्रयोग और सहमति के माध्यम से बनाए रखने वाले शासन के रूप में देखा।
(B) ग्राम्शी का मानना था कि क्रांति के तुरंत बाद राज्य समाप्त हो जाएगा।
(C) ग्राम्शी ने तर्क दिया कि राज्य प्रतिस्पर्धी वर्ग हितों के बीच एक तटस्थ मध्यस्थ था।
(D) ग्राम्शी ने राज्य को वर्ग शासन के एक साधन के रूप में मानने के विचार को पूरी तरह से अस्वीकृत कर दिया।

80. लोकतंत्र पर जे.एस. मिल के विचारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. वे बिना किसी योग्यता के सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के समर्थक थे।
2. उन्होंने बहुल मतदान की एक प्रणाली का प्रस्ताव दिया, जिसमें शिक्षितों को अधिक मत दिए जाते थे।
3. वे मतदाताओं को दबाव से बचाने के लिए गुप्त मतदान के प्रबल समर्थक थे। उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल 2
(B) केवल 1 और 3
(C) केवल 2 और 3
(D) 1, 2 और 3

81. निम्नलिखित में से कौन उदारवाद की समुदायवादी आलोचना से नहीं जुड़ा है?
(A) अलास्डेयर मैकिन्टायर
(B) जॉन रॉल्स
(C) माइकल वाल्ज़र
(D) चार्ल्स टेलर

82. सावरकर की 'हिंदुत्व' की अवधारणा मुख्य रूप से है:
(A) हिंदू राष्ट्र की पहचान को परिभाषित करने वाली एक राजनीतिक और सांस्कृतिक अवधारणा।
(B) विशिष्ट अनुष्ठानों और देवताओं पर आधारित एक धार्मिक अवधारणा।
(C) जाति व्यवस्था को समाप्त करने पर केंद्रित एक सामाजिक सुधार आंदोलन।
(D) अद्वैत वेदांत पर आधारित एक दार्शनिक प्रणाली।

83. अरस्तू के लिए, सरकार का सबसे अच्छा 'व्यवहार्य' रूप कौन सा है?
(A) दार्शनिक राजा द्वारा शासित आदर्श राज्य।
(B) कुलीनतंत्र, गुणी कुछ लोगों का शासन।
(C) पॉलिटी, मध्यम वर्ग द्वारा चलाई जाने वाली एक संवैधानिक सरकार।
(D) शुद्ध लोकतंत्र, जहाँ सभी नागरिक शासन करते हैं और बारी-बारी से शासित होते हैं।

84. 'स्वतंत्र होने के लिए बाध्य' वाक्यांश किसके राजनीतिक विचार का एक विवादित भाग है?
(A) जे.एस. मिल
(B) टी.एच. ग्रीन
(C) थॉमस हॉब्स
(D) ज्यां-जैक रूसो

Click Here to Buy book on Amazon

85. शांति पर्व में, 'मात्स्यन्याय' की अवधारणा किसका वर्णन करती है?
(A) एक सुव्यवस्थित राज्य जहाँ शक्तिशाली लोग कमजोरों की रक्षा करते हैं।
(B) नौसैनिक युद्ध और समुद्री व्यापार के सिद्धांत।
(C) प्रकृति की एक ऐसी अवस्था जहाँ बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को खा जाती हैं, जो अराजकता का प्रतीक है।
(D) नदियों और समुद्रों में मछली पकड़ने के अधिकारों को नियंत्रित करने वाली एक कानूनी संहिता।

86. अभिकथन (A): रॉबर्ट नोजिक एक न्यूनतम राज्य की वकालत करते हैं जिसके कार्य बल प्रयोग, चोरी, धोखाधड़ी से सुरक्षा और अनुबंधों के प्रवर्तन तक सीमित हैं।
कारण (R): इससे अधिक विस्तृत कोई भी राज्य दूसरों की सहायता करने के लिए कुछ व्यक्तियों पर जबरन कर लगाकर व्यक्तिगत अधिकारों, विशेष रूप से संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन करेगा।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

87. कार्ल मार्क्स के अधिशेष मूल्य का सिद्धांत कहता है कि:
(A) अधिशेष मूल्य निवेश और जोखिम के लिए पूंजीपति द्वारा अर्जित लाभ है।
(B) अधिशेष मूल्य अतिरिक्त समय के लिए श्रमिकों को दिया जाने वाला अतिरिक्त वेतन है।
(C) अधिशेष मूल्य समाज द्वारा उत्पादित अतिरिक्त वस्तुएं हैं जिन्हें आवश्यकता के अनुसार वितरित किया जाता है।
(D) अधिशेष मूल्य उत्पादित मूल्य और भुगतान किए गए वेतन के बीच का अंतर है।

88. जॉन रॉल्स की मूल स्थिति में चुने गए न्याय के दो सिद्धांत हैं:
(A) समान बुनियादी स्वतंत्रता का सिद्धांत और भेद का सिद्धांत।
(B) उपयोगिता का सिद्धांत और समानता का सिद्धांत।
(C) हकदारी का सिद्धांत और सुधार का सिद्धांत।
(D) आत्म-संरक्षण का सिद्धांत और शक्ति के अधिकतमकरण का सिद्धांत।

89. सूची I के विचारधारा संप्रदाय का सूची II के केंद्रीय विचार के साथ मिलान करें।
सूची I:
P. प्राचीन ग्रीक विचार
Q. सामाजिक अनुबंध सिद्धांत
R. उपयोगितावाद
S. समकालीन उदारतावाद
सूची II:
1. अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य एक आवश्यक बुराई के रूप में
2. अच्छे जीवन की प्राप्ति के लिए पोलिस एक प्राकृतिक संस्था के रूप में
3. सहमति पर आधारित सरकार की वैधता
4. सुख का अधिकतमकरण और दुख का न्यूनतमकरण।
(A) P-2, Q-3, R-4, S-1
(B) P-3, Q-2, R-4, S-1
(C) P-2, Q-4, R-3, S-1
(D) P-1, Q-3, R-4, S-2

90. संरक्षक वर्गों के लिए प्लेटो के 'संपत्ति और पत्नियों के साम्यवाद' का मुख्य उद्देश्य क्या था?
(A) ध्यान भटकाने वाली वस्तुओं और निजी हितों के स्रोतों को समाप्त करना, जिससे राज्य के प्रति उनकी निष्ठा सुनिश्चित हो सके।
(B) पूरे राज्य में आर्थिक समानता को बढ़ावा देना।
(C) महिलाओं को पारंपरिक पारिवारिक भूमिकाओं से मुक्त करना।
(D) सभी नागरिकों के लिए मुक्त प्रेम और सांप्रदायिक जीवन पर आधारित समाज बनाना।

91. किस आधुनिक भारतीय विचारक ने विकेंद्रीकृत भारतीय राजनीति की नींव के रूप में 'समुदायवादी लोकतंत्र' या 'पंचायती राज' के मॉडल की वकालत की?
(A) एम.एन. रॉय
(B) बी.आर. अंबेडकर
(C) अरविंदो घोष
(D) जय प्रकाश नारायण

92. लेनिन की 'वेंगार्ड पार्टी' की अवधारणा किसे संदर्भित करती है?
(A) उन सभी के लिए खुली एक जन-आधारित पार्टी जो शामिल होना चाहते हैं।
(B) सर्वहारा वर्ग का नेतृत्व करने के लिए पेशेवर क्रांतिकारियों की एक लघु, अनुशासित और केंद्रीय रूप से संगठित पार्टी।
(C) विभिन्न समाजवादी दलों का गठबंधन।
(D) एक अस्थायी राजनीतिक संगठन जो क्रांति के बाद भंग हो जाता है।

93. निम्नलिखित आधुनिक भारतीय विचारकों को उनके जन्म के सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें:
1. एम.के. गांधी
2. बी.आर. अंबेडकर
3. वी.डी. सावरकर
4. एम.एन. रॉय।
(A) 1, 3, 4, 2
(B) 1, 4, 3, 2
(C) 3, 1, 4, 2
(D) 4, 1, 3, 2

94. टी.एच. ग्रीन का "सामान्य हित" से क्या तात्पर्य है?

NODIA

(A) व्यक्तिगत निजी हितों का कुल योग।
(B) समग्र रूप से राष्ट्र की भौतिक समृद्धि।
(C) लोकतांत्रिक चुनावों के माध्यम से व्यक्त बहुमत की इच्छा।
(D) एक ऐसा सामाजिक वातावरण जो व्यक्तियों को उनके नैतिक और बौद्धिक आत्म-साक्षात्कार को प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।

95. कौटिल्य के शासन-कला के संदर्भ में, 'साम, दाम, दंड, भेद' क्या हैं?
(A) शासन-कला या कूटनीति के चार साधन।
(B) सप्तांग सिद्धांत के चार तत्व।
(C) चार प्रकार के गुप्तचर जो राजा को नियुक्त करने चाहिए।
(D) न्यायिक प्रणाली के चार स्तर।

96. लॉक के अनुसार, सामाजिक अनुबंध क्या सृजित करता है?
(A) असीमित शक्ति वाला एक पूर्ण संप्रभु।
(B) पहले एक नागरिक समाज, और फिर एक सरकार या राजनीतिक समाज।
(C) एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र जहाँ नागरिक स्वयं कानून बनाते हैं।
(D) एक समाजवादी राज्य जो निजी संपत्ति को समाप्त करता है।

97. ग्राम्शी के विचार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. उन्होंने 'गति के युद्ध' और 'स्थिति के युद्ध' के बीच अंतर किया।
2. उन्होंने 'जैविक बुद्धिजीवी' की अवधारणा प्रस्तुत की।
3. उन्होंने तर्क दिया कि सर्वहारा क्रांति केवल उन्नत पूंजीवादी देशों में ही संभव थी।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2, और 3

98. प्लेटो के पत्नियों और संपत्ति के साम्यवाद की अरस्तू की आलोचना का मुख्य कारण यह था कि:
(A) यह परिवार और निजी संपत्ति की संस्थाओं को नष्ट कर देगा, जिन्हें वे स्वाभाविक और आवश्यक मानते थे।
(B) इसे व्यवहार में लागू करना अत्यंत कठिन था।
(C) यह पर्याप्त नहीं था और इसे पूरी जनसंख्या पर लागू किया जाना चाहिए था।
(D) यह स्पार्टा के लोगों से लिया गया विचार था और इसलिए मौलिक नहीं था।

99. "द सबजेक्शन ऑफ विमेन" में, जे.एस. मिल तर्क देते हैं कि एक लिंग की दूसरे के प्रति कानूनी अधीनता है:
(A) एक प्राकृतिक और हितकारी व्यवस्था।
(B) कम विकसित समाजों में एक अस्थायी आवश्यकता।
(C) अपने आप में गलत और मानव सुधार की मुख्य बाधाओं में से एक।
(D) उपयोगितावादी आधार पर उचित क्योंकि यह अधिकतम सुख उत्पन्न करती है।

100. माओ जेदोंग ने किसकी क्रांतिकारी क्षमता पर बल देकर मार्क्सवाद-लेनिनवाद को चीन की स्थितियों के अनुरूप ढाला?
(A) शहरी सर्वहारा
(B) बुद्धिजीवी वर्ग
(C) राष्ट्रीय बुर्जुआ वर्ग
(D) किसान वर्ग

101. अभिकथन (A): हॉब्स के विपरीत, लॉक सीमित शक्तियों वाली सरकार के लिए तर्क देते हैं।
कारण (R): लॉक का मानना था कि कुछ प्राकृतिक अधिकार अपरिहार्य हैं और सरकार एक न्यास है, जिसे यदि वह अत्याचारी हो जाती है तो भंग किया जा सकता है।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

NODIA

102. किस विचारक ने तर्क दिया कि राज्य "पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण" है, जो तर्क और नैतिकता के उच्चतम अवतार का प्रतिनिधित्व करता है?
(A) कार्ल मार्क्स
(B) जी.डब्ल्यू.एफ. हेगेल
(C) थॉमस हॉब्स
(D) जेरेमी बेंथम

103. एम.के. गांधी की 'ग्राम स्वराज' की अवधारणा एक ऐसे समाज की कल्पना करती है जहाँ:
(A) केंद्र सरकार सभी ग्रामीण गतिविधियों को नियंत्रित करती है।
(B) गांवों को बड़े औद्योगिक समूहों में संगठित किया जाता है।
(C) एक राष्ट्रीय नेता सीधे ग्राम परिषदों द्वारा चुना जाता है।
(D) प्रत्येक गाँव एक आत्मनिर्भर और स्वशासित गणराज्य है।

104. कौटिल्य के अर्थशास्त्र में विश्लेषण की मुख्य वस्तु 'विजिगीषु' है, जो संदर्भित करता है:
(A) संभावित विजेता या महत्वाकांक्षी राजा को।
(B) आदर्श नागरिक को।
(C) पड़ोसी शत्रु को।
(D) तटस्थ मध्यस्थ राजा को।

105. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिन्हें कथन I और कथन II के रूप में अंकित किया गया है।
कथन I: मार्क्स के लिए, 'सर्वहारा वर्ग की तानाशाही' इतिहास

का अंतिम चरण है।
कथन II: सर्वहारा वर्ग की तानाशाही एक संक्रमणकालीन चरण है जो एक वर्गहीन, कम्युनिस्ट समाज की ओर ले जाता है जहाँ राज्य तिरोहित हो जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।
(D) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।

106. ग्राम्शी के सिद्धांत में 'जैविक बुद्धिजीवी' की अवधारणा किसे संदर्भित करती है?
(A) वे विचारक जो सर्वहारा वर्ग जैसे मौलिक सामाजिक वर्ग से उभरते हैं और उनके हितों को व्यक्त करते हैं।
(B) पारंपरिक जमींदार वर्ग के बुद्धिजीवी।
(C) विश्वविद्यालय के शिक्षाविद जो सामाजिक संघर्षों से पृथक हैं।
(D) राज्य द्वारा नियोजित नौकरशाह जो सार्वजनिक संस्थानों का प्रबंधन करते हैं।

107. निम्नलिखित में से कौन जय प्रकाश नारायण की 'सम्पूर्ण क्रांति' के सार को सबसे अच्छी तरह व्यक्त करता है?
(A) एक क्रांतिकारी दल द्वारा राज्य की सत्ता पर हिंसक कब्जा।
(B) केंद्रीय प्राधिकरण को मजबूत करने के लिए संवैधानिक संशोधनों की एक श्रृंखला।
(C) विशेष रूप से तीव्र औद्योगिकीकरण पर केंद्रित एक आर्थिक कार्यक्रम।
(D) समाज और व्यक्ति का एक शांतिपूर्ण, बहुआयामी परिवर्तन।

108. सूची I के लेखकों का सूची II की प्रसिद्ध कृतियों के साथ मिलान करें।
सूची I:
P. बी.आर. अंबेडकर
Q. वी.डी. सावरकर
R. एम.के. गांधी
S. अरविंदो घोष
सूची II:
1. द लाइफ डिवाइन
2. हिंद स्वराज
3. एसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व
4. एनीहिलेशन ऑफ कास्ट।
(A) P-3, Q-4, R-1, S-2
(B) P-4, Q-3, R-2, S-1
(C) P-4, Q-2, R-3, S-1
(D) P-1, Q-3, R-2, S-4

109. 'स्व-विषयक' और 'पर-विषयक' कार्यों के बीच का अंतर किसके राजनीतिक सिद्धांत के लिए महत्वपूर्ण है?
(A) प्लेटो
(B) थॉमस हॉब्स
(C) जे.एस. मिल
(D) कार्ल मार्क्स

110. लॉक की प्राकृतिक अवस्था में, प्राकृतिक कानून का निष्पादन हर व्यक्ति के हाथ में है। इस स्थिति की मुख्य असुविधा क्या है?
(A) लोग प्राकृतिक कानून को लागू करने के लिए अत्यंत दुर्बल हैं।
(B) सभी के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं हैं, जिससे निरंतर संघर्ष होता है।
(C) प्राकृतिक कानून आम लोगों के समझने के लिए बहुत जटिल है।
(D) व्यक्तिगत पूर्वाग्रह और आवेग लोगों को उनके अपने मामलों में खराब न्यायाधीश बनाते हैं।

111. सावरकर के अनुसार, वे तीन अनिवार्य बंधन कौन से हैं जो हिंदुओं को एक राष्ट्र के रूप में जोड़ते हैं?
(A) समान क्षेत्र (राष्ट्र), समान जाति (जाति), और समान संस्कृति (संस्कृति)।
(B) समान भाषा, समान आहार और समान अनुष्ठान।
(C) वेदों का पालन, पुनर्जन्म में विश्वास और जाति प्रथा।
(D) साझा राजनीतिक दल, साझा आर्थिक हित और एक साझा सम्राट।

112. अरस्तू के क्रांति के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. उन्होंने क्रांति को संविधान में किसी भी परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया।
2. उनका मानना था कि क्रांति का मुख्य कारण समानता या असमानता की लालसा है।
3. उन्होंने सुझाव दिया कि निरंकुश शासन सरकार का सबसे स्थिर रूप है।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2, और 3

113. यह विचार कि एक वैध राज्य 'शासितों की सहमति' पर आधारित होना चाहिए, किसके विचार की आधारशिला है?
(A) प्लेटो
(B) जॉन लॉक
(C) मैकियावेली
(D) जी.डब्ल्यू.एफ. हेगेल

114. ग्राम्शी के लिए, 'नागरिक समाज' किसका क्षेत्र है?
(A) निजी या गैर-राज्य संस्थान जैसे चर्च, विद्यालय और ट्रेड यूनियन।
(B) राज्य का दमनकारी तंत्र।
(C) उत्पादन का आर्थिक आधार।

Downloaded from www.pdf.tube

(D) राष्ट्रों का अंतर्राष्ट्रीय समुदाय।

115. निम्नलिखित विचारकों में से कौन 'रेडिकल ह्युमनिज्म' की वकालत के लिए जाना जाता है?
(A) अरविंदो घोष
(B) जय प्रकाश नारायण
(C) एम.एन. रॉय
(D) बी.आर. अंबेडकर

116. "एक असंतुष्ट मानव होना एक संतुष्ट सूअर होने से बेहतर है; एक असंतुष्ट सुकरात होना एक संतुष्ट मूर्ख होने से बेहतर है।" यह उद्धरण जे.एस. मिल के किस बात पर बल को दर्शाता है?
(A) सुख का मात्रात्मक माप।
(B) सुख की खोज की व्यर्थता।
(C) पशु कल्याण का मूल्य।
(D) उच्च सुखों की गुणात्मक श्रेष्ठता।

117. निम्नलिखित पुस्तकों के प्रकाशन को सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें:
1. लेविआथन
2. द प्रिंस
3. टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट
4. द सोशल कॉन्ट्रैक्ट।
(A) 2, 1, 3, 4
(B) 1, 2, 3, 4
(C) 2, 3, 1, 4
(D) 3, 1, 2, 4

118. कौन सा कथन मैकियावेली के विचार में 'वीरता' और 'भाग्य' के बीच संबंध का सटीक वर्णन करता है?
(A) 'वीरता' भाग्य को पूरी तरह से नियंत्रित करने की क्षमता है।
(B) 'भाग्य' मानवीय मामलों के लगभग आधे भाग को नियंत्रित करता है, जबकि 'वीरता' शेष को आकार दे सकती है।
(C) 'भाग्य' सर्वशक्तिमान है, और मानवीय 'वीरता' अप्रासंगिक है।
(D) 'वीरता' और 'भाग्य' धार्मिक अवधारणाएं हैं जिन्हें एक राजकुमार को अपनाना चाहिए।

119. प्लेटो के आदर्श राज्य में, कौन सा वर्ग साहस के गुण से जुड़ा है?
(A) शासक
(B) उत्पादक
(C) दार्शनिक
(D) सहायक (सैनिक)

120. अभिकथन (A): बी.आर. अंबेडकर दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल के प्रबल समर्थक थे।
कारण (R): उनका मानना था कि केवल पृथक निर्वाचक मंडल के माध्यम से ही दलित वर्ग वास्तविक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कर सकते हैं और हिंदू बहुसंख्यक वर्ग के वर्चस्व से अपने हितों की रक्षा कर सकते हैं।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

121. शांति पर्व में 'दंडनीति' की अवधारणा किसके लिए आवश्यक मानी गई है?
(A) आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त करना।
(B) देवताओं को प्रसन्न करने के लिए धार्मिक यज्ञ करना।
(C) समाज को अराजकता में गिरने से रोकना।
(D) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य का संचालन करना।

122. रूसो 'सभी की इच्छा' और 'सामान्य इच्छा' के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर करते हैं। 'सभी की इच्छा' है:
(A) निजी, स्वार्थी हितों का योग।
(B) हमेशा सही और सामान्य हित का लक्ष्य।
(C) राज्य में बहुमत वाले गुट की इच्छा।
(D) देश के कानून का दूसरा नाम।

123. 'भेद का सिद्धांत' रॉल्स के न्याय के दूसरे सिद्धांत का दूसरा भाग है। उस दूसरे सिद्धांत का पहला भाग है:
(A) सभी के लिए समान बुनियादी स्वतंत्रता का सिद्धांत।
(B) अवसर की उचित समानता।
(C) धारित वस्तुओं के उचित हस्तांतरण का सिद्धांत।
(D) उपयोगिता अधिकतमकरण का सिद्धांत।

124. निम्नलिखित में से कौन सी एम.एन. रॉय की रेडिकल डेमोक्रेसी की अवधारणा की विशेषता नहीं है?
(A) सत्ता का विकेंद्रीकरण
(B) एक ही दल द्वारा नियंत्रित अत्यधिक केंद्रीकृत राज्य
(C) पीपुल्स समितियों के एक नेटवर्क का निर्माण
(D) राजनीतिक दलों का उन्मूलन

125. टी.एच. ग्रीन के लिए, स्वतंत्रता है:
(A) सभी नियंत्रणों की अनुपस्थिति।
(B) जो कोई चाहता है वह करने की स्वतंत्रता।
(C) कुछ करने या आनंद लेने योग्य कार्य करने या आनंद लेने की एक सकारात्मक क्षमता।
(D) संप्रभु द्वारा दिया गया एक अधिकार जिसे किसी भी समय रद्द किया जा सकता है।

126. सूची I के विचारकों का सूची II के मूल विचारों के साथ मिलान करें।
सूची I:
P. रॉबर्ट नोजिक
Q. जॉन रॉल्स
R. माइकल सैंडेल
S. एंटोनियो ग्राम्शी

सूची II:
1. निष्पक्षता के रूप में न्याय
2. "असंलग्न स्व" की आलोचना
3. सांस्कृतिक हेजेमनी
4. न्याय का हकदारी सिद्धांत।

(A) P-1, Q-4, R-2, S-3
(B) P-4, Q-1, R-3, S-2
(C) P-4, Q-1, R-2, S-3
(D) P-2, Q-3, R-1, S-4

127. हॉब्स के "लेविआथन" में, संप्रभु है:
(A) अनुबंध का पक्षकार नहीं है और उसके पास पूर्ण, असीमित शक्ति है।
(B) नागरिकों की तरह ही सामाजिक अनुबंध से बंधा हुआ है।
(C) उच्च धार्मिक प्राधिकरण के प्रति उत्तरदायी है।
(D) लोगों द्वारा चुनी गई प्रतिनिधियों की एक समिति।

128. "हिंद स्वराज" में गांधी की आधुनिक सभ्यता की आलोचना मुख्य रूप से किस पर लक्षित है?
(A) तकनीकी प्रगति पर बल।
(B) अनैतिकता और भौतिकवाद।
(C) लोकतांत्रिक राजनीतिक संस्थान।
(D) वैज्ञानिक और तर्कसंगत दृष्टिकोण।

129. निम्नलिखित विचारकों पर विचार करें:
1. जॉन लॉक
2. थॉमस हॉब्स
3. ज्यां-जैक रूसो

उपरोक्त में से किसने प्राकृतिक अवस्था को शांति, सद्भावना, आपसी सहायता और संरक्षण की स्थिति के रूप में वर्णित किया?
(A) केवल 2
(B) केवल 1
(C) केवल 1 और 3
(D) केवल 2 और 3

130. अरविंदो घोष के 'आध्यात्मिक राष्ट्रवाद' के विचार ने सुझाव दिया कि भारत की राष्ट्रीयता थी:
(A) एक दैवीय वास्तविकता, एक आध्यात्मिक ऊर्जा जिसे अनुभव करने की आवश्यकता थी।
(B) अंग्रेजों द्वारा निर्मित एक राजनीतिक संरचना।
(C) विभिन्न प्रांतों का एक आर्थिक संघ।
(D) भाषा और जातीयता पर आधारित एक सांस्कृतिक पहचान।

131. निम्नलिखित में से किस विचारक ने प्रसिद्ध रूप से कहा था कि सरकार का उद्देश्य "जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति" की रक्षा करना है?
(A) थॉमस हॉब्स
(B) ज्यां-जैक रूसो
(C) जॉन लॉक
(D) कार्ल मार्क्स

132. "एनीहिलेशन ऑफ कास्ट" में बी.आर. अंबेडकर का मुख्य तर्क यह है कि:
(A) जाति व्यवस्था को केवल अस्पृश्यता को समाप्त करके सुधारा जा सकता है।
(B) अंतर-जातीय खान-पान और अंतर-जातीय विवाह प्रभावी समाधान नहीं हैं।
(C) आर्थिक प्रगति से जाति का स्वतः ही अंत हो जाएगा।
(D) वास्तविक उपाय उन धार्मिक धारणाओं को नष्ट करना है जिन पर जाति आधारित है।

133. अरस्तू के अनुसार, राज्य का अंतिम उद्देश्य क्या है?
(A) सैन्य सुरक्षा और आर्थिक समृद्धि प्रदान करना।
(B) एक अनुबंध लागू करना जो प्रकृति की अवस्था को समाप्त करता है।
(C) नागरिकों को अच्छा जीवन प्राप्त करने में सक्षम बनाना।
(D) सबसे शक्तिशाली वर्ग के हितों की सेवा करना।

134. "प्रत्येक से उसकी क्षमता के अनुसार, प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार" एक ऐसा सिद्धांत है जिसे कार्ल मार्क्स का मानना था कि कहाँ संचालित होगा:
(A) पूंजीवादी समाज
(B) कम्युनिस्ट समाज (उच्च चरण)
(C) सामंती समाज
(D) समाजवादी समाज (साम्यवाद का निचला चरण)

135. राजकुमार को मैकियावेली की सलाह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. एक राजकुमार को हमेशा गुणी होना चाहिए और अपने वादे निभाने चाहिए।
2. एक राजकुमार को गुणी दिखना चाहिए, लेकिन यदि आवश्यक हो तो विपरीत कार्य करने के लिए तैयार रहना चाहिए।
3. एक राजकुमार को अपनी प्रजा द्वारा प्रेम किए जाने के बजाय डरा हुआ होना चाहिए।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल 1 और 3
(B) केवल 2
(C) केवल 2 और 3
(D) 1, 2, और 3

136. लेनिन ने "व्हाट इज टू बी डन?" में तर्क दिया कि समाजवादी चेतना:
(A) बुद्धिजीवियों के एक अग्रगामी दल द्वारा बाहर से श्रमिक वर्ग में लाई जानी चाहिए।
(B) श्रमिक वर्ग के बीच उनके आर्थिक संघर्षों के दौरान स्वतः ही उत्पन्न होती है।
(C) सभी उत्पीड़ित लोगों की एक अंतर्निहित विशेषता है।
(D) राज्य के तिरोहित होने के बाद ही प्राप्त की जा सकती है।

Click Here to Buy book on Amazon

137. 'सप्तांग' या राज्य के सात अंगों की अवधारणा का विस्तार से वर्णन किसमें किया गया है?
(A) शांति पर्व
(B) प्लेटो का रिपब्लिक
(C) कौटिल्य का अर्थशास्त्र
(D) मनुस्मृति

138. अभिकथन (A): जे.एस. मिल एक अनिच्छुक लोकतांत्रिक थे, जो "बहुमत की निरंकुशता" से भयभीत थे।
कारण (R): उन्होंने अल्पसंख्यकों और शिक्षितों की राय को अशिक्षित जनता से बचाने के लिए बहुल मतदान और आनुपातिक प्रतिनिधित्व जैसे उपायों का प्रस्ताव दिया।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

139. माओ के राजनीतिक विचार में, 'मास लाइन' नेतृत्व की एक विधि है जिसमें शामिल है:
(A) जनता पर दल की पूर्व-निर्धारित नीतियों को थोपना।
(B) जनता की इच्छा निर्धारित करने के लिए नियमित चुनाव कराना।
(C) मार्गदर्शन के लिए विशेष रूप से सबसे उन्नत वर्गों पर निर्भर करना।
(D) जनता के बिखरे हुए विचारों को संकलित करना और उन्हें नीति के रूप में वापस करना।

140. किस विचारक ने प्रसिद्ध रूप से 'राज्य' और 'नागरिक समाज' के बीच अंतर किया, बाद वाले को विशिष्टता और स्वार्थ के क्षेत्र के रूप में देखा जो अंततः राज्य की उच्च सार्वभौमिकता में समन्वित हो जाता है?
(A) जॉन लॉक
(B) जी.डब्ल्यू.एफ. हेगेल
(C) कार्ल मार्क्स
(D) जे.एस. मिल

141. रॉबर्ट नोजिक की "एनार्की, स्टेट, एंड यूटोपिया" का मुख्य तर्क किसका बचाव है?
(A) अराजकतावाद
(B) एक पुनर्वितरणकारी कल्याणकारी राज्य
(C) एक न्यूनतम, नाइट-वॉचमैन राज्य
(D) एक समुदायवादी राज्य

142. प्लेटो और अरस्तू की पद्धतियों के बीच एक प्रमुख अंतर यह है कि:
(A) प्लेटो एक अनुभववादी थे, जबकि अरस्तू एक तर्कवादी थे।
(B) प्लेटो ऐतिहासिक विश्लेषण पर निर्भर थे, जबकि अरस्तू अमूर्त रूपों पर केंद्रित थे।
(C) प्लेटो एक राजनीतिक वैज्ञानिक थे, जबकि अरस्तू एक नैतिक दार्शनिक थे।
(D) प्लेटो की पद्धति निगमनात्मक और आदर्शवादी थी, जबकि अरस्तू की अधिक अनुभवजन्य और पर्यवेक्षणात्मक थी।

143. निम्नलिखित में से कौन सा विचारक और उनकी अवधारणा का गलत मेल है?
(A) जय प्रकाश नारायण - आध्यात्मिक राष्ट्रवाद
(B) गांधी - ट्रस्टीशिप
(C) एम.एन. रॉय - रेडिकल ह्युमनिज्म
(D) अंबेडकर - जाति का विनाश

144. रूसो के अनुसार, सरकार का एकमात्र वैध रूप क्या है?
(A) संवैधानिक राजतंत्र
(B) एक गणराज्य जिसमें लोग संप्रभु हैं और सीधे कानून बनाते हैं।
(C) सबसे गुणी नागरिकों का एक कुलीनतंत्र।
(D) एक परोपकारी तानाशाही।

145. शांति पर्व राजा को कर वसूलने की सलाह देता है:
(A) कोष भरने के लिए जितना संभव हो उतना।
(B) जैसे मधुमक्खी पुष्पों को क्षति पहुँचाए बिना उनसे मधु एकत्र करती है।
(C) केवल सबसे धनी व्यापारियों और भूस्वामियों से।
(D) इस तरह से कि नागरिकों के पास जीवित रहने के लिए न्यूनतम ही बचे।

NODIA

146. कार्ल मार्क्स के लिए, पूंजीवादी समाज में मुख्य अंतर्विरोध किसके बीच है?
(A) उत्पादन की शक्तियों और उत्पादन के संबंधों के बीच।
(B) राष्ट्रीय बुर्जुआ और साम्राज्यवादी शक्तियों के बीच।
(C) राज्य और नागरिक समाज के बीच।
(D) भूस्वामी कुलीनतंत्र और औद्योगिक बुर्जुआ के बीच।

147. निम्नलिखित विचारधाराओं को उनके उभरने के सही क्रम में व्यवस्थित करें:
1. ग्रीक राजनीतिक विचार
2. समकालीन समुदायवाद
3. यूरोपीय प्रबोधन विचार
4. उपयोगितावाद।
(A) 1, 3, 4, 2
(B) 1, 4, 3, 2
(C) 3, 1, 4, 2
(D) 1, 3, 2, 4

148. गांधी का 'सत्याग्रह' से क्या तात्पर्य है?
(A) स्वतंत्रता के लिए सशस्त्र संघर्ष।
(B) दुर्बलता के कारण निष्क्रिय प्रतिरोध।
(C) एक राजनीतिक वार्ता की रणनीति।
(D) "सत्य की शक्ति" या "आत्मिक शक्ति," विरोध की एक अहिंसक पद्धति।

149. सूची I के शब्दों का सूची II की परिभाषाओं के साथ मिलान करें।
सूची I:
P. अमात्य
Q. जनपद
R. दुर्ग
S. कोष
सूची II:
1. किलेबंद राजधानी
2. क्षेत्र और लोग
3. मंत्री / नौकरशाही
4. संचित धन।
(A) P-3, Q-2, R-1, S-4
(B) P-2, Q-3, R-1, S-4
(C) P-3, Q-1, R-2, S-4
(D) P-4, Q-2, R-1, S-3

150. उदारवाद की अपनी आलोचना में, माइकल सैंडेल का 'असंलग्न स्व' से क्या तात्पर्य है?
(A) एक ऐसा स्व जो सभी सामाजिक और राजनीतिक उत्तरदायित्वों से मुक्त है।
(B) एक ऐसा स्व जो चयन करने के लिए अपने इतिहास, समुदाय और मूल्यों से पृथक खड़ा हो सकता है।
(C) एक व्यक्ति जिसने वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है।
(D) एक व्यक्ति जो सामाजिक अनुबंध से पूर्व प्राकृतिक अवस्था में रहता है।

151. हॉब्स के 'लेविआथन' के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. यह एक नश्वर ईश्वर है जिसके प्रति हम अपनी शांति और रक्षा के ऋणी हैं।
2. इसकी प्रजा द्वारा उस पर अन्याय का आरोप लगाया जा सकता है।
3. इसकी शक्ति अविभाज्य और अक्षुण्ण है।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल 1 और 3
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2, और 3

152. टी.एच. ग्रीन के राजनीतिक दर्शन को किसका एक रूप माना जाता है?
(A) सामाजिक उदारवाद या नया उदारवाद
(B) नकारात्मक उदारवाद
(C) उदारतावाद
(D) मार्क्सवाद

153. प्लेटो के "रिपब्लिक" का एक केंद्रीय तर्क यह है कि एक न्यायपूर्ण राज्य वह है जिसमें:
(A) शासन में सभी नागरिकों की समान भागीदारी होती है।
(B) व्यक्तिगत स्वतंत्रता अधिकतम होती है।
(C) शासक सर्वाधिक बुद्धिमान होते हैं, सैनिक सर्वाधिक साहसी होते हैं, और उत्पादक अपना कार्य करते हैं।
(D) कानून बहुमत द्वारा निर्मित किए जाते हैं।

154. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिन्हें कथन I और कथन II के रूप में अंकित किया गया है।
कथन I: बेंथम लोकतंत्र, कानूनी सुधार और कानून के संहिताकरण के प्रबल समर्थक थे।
कथन II: उनका मानना था कि प्रथा और दृष्टांत पर आधारित पारंपरिक कानून तर्कहीन थे और शक्तिशाली लोगों के हितों की सेवा करते थे। उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
(D) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।

155. जय प्रकाश नारायण के लिए, 'दलविहीन लोकतंत्र' किसके माध्यम से साकार होगा?
(A) एक सैन्य तख्तापलट जो सभी राजनीतिक दलों को समाप्त कर देता है।
(B) एक-दलीय राज्य व्यवस्था।
(C) एक ऐसा चुनाव जहाँ केवल स्वतंत्र प्रत्याशी ही चुनाव लड़ सकते हैं।
(D) समुदायवादी परिषदों की एक जमीनी स्तर की व्यवस्था।

156. बल और धोखाधड़ी की दो तलवारें, हॉब्स के लिए, किसमें प्रमुख गुण हैं:
(A) एक सुव्यवस्थित राष्ट्रमंडल।
(B) युद्ध की स्थिति।
(C) अंतर्राष्ट्रीय संबंध।
(D) न्यायालय कक्ष।

157. निम्नलिखित में से किसे 'समुदायवादी' विचारधारा का प्रमुख विचारक माना जाता है?
(A) रॉबर्ट नोजिक
(B) जॉन रॉल्स
(C) माइकल वाल्ज़र
(D) फ्रेडरिक हायेक

158. "अब तक के सभी विद्यमान समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है।" यह किसकी शुरुआती पंक्ति है?
(A) दास कैपिटल
(B) द जर्मन आइडियोलॉजी
(C) द एटीनथ ब्रुमेयर ऑफ लुई बोनापार्ट
(D) द कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो

159. अभिकथन (A): ग्राम्शी ने तर्क दिया कि पश्चिम में पूंजीवादी राज्य को उखाड़ फेंकने के लिए 'गति के युद्ध' के स्थान पर 'स्थिति के युद्ध' की आवश्यकता थी।
कारण (R): पश्चिमी समाजों में, शासक वर्ग की शक्ति एक जटिल नागरिक समाज में गहराई से निहित है, और राज्य पर

Downloaded from www.pdf.tube

प्रत्यक्ष प्रहार के सफल होने से पूर्व उसकी हेजेमनी को धीरे-धीरे दुर्बल किया जाना चाहिए।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

160. रॉल्स के सिद्धांत में 'मूल स्थिति' का मूलभूत उद्देश्य क्या है?
(A) वास्तव में घटित एक ऐतिहासिक घटना का वर्णन करना।
(B) न्याय के निष्पक्ष सिद्धांतों को प्राप्त करने के लिए एक काल्पनिक विचार प्रयोग के रूप में कार्य करना।
(C) एक ऐसा राज्य निर्मित करना जो समग्र उपयोगिता को अधिकतम करे।
(D) एक न्यूनतम, नाइट-वॉचमैन राज्य का औचित्य सिद्ध करना।

161. कौटिल्य के अनुसार, एक राजा की विदेश नीति मुख्य रूप से किसके द्वारा निर्देशित होनी चाहिए?
(A) नैतिक और अनैतिक सिद्धांत।
(B) राष्ट्रीय स्व-हित और शक्ति की खोज।
(C) विश्व सरकार स्थापित करने का लक्ष्य।
(D) विद्यमान शक्ति संतुलन का संरक्षण।

162. निम्नलिखित में से कौन गांधी के 'सर्वोदय' कार्यक्रम का भाग नहीं है?
(A) केंद्रीकृत भारी औद्योगिकीकरण
(B) ट्रस्टीशिप
(C) ग्राम स्वराज
(D) स्वदेशी

163. अरस्तू का सरकार का वर्गीकरण दो मानदंडों पर आधारित है:
(A) राज्य का आकार और उसकी सैन्य शक्ति।
(B) आर्थिक व्यवस्था और नागरिक भागीदारी का स्तर।
(C) शासकों की संख्या और उनके शासन का उद्देश्य।
(D) नागरिकों की जातीय संरचना और धर्म का रूप।

164. लॉक के संपत्ति के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. प्राकृतिक अवस्था में, पृथ्वी मानव जाति को समान रूप से प्रदान की गई है।
2. एक व्यक्ति प्राकृतिक संसाधनों के साथ अपने श्रम को सम्मिलित करके संपत्ति प्राप्त करता है।
3. प्राकृतिक अवस्था में कोई व्यक्ति कितनी संपत्ति संचित कर सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1
(D) 1, 2, और 3

165. माओ जेदोंग के विचार में 'न्यू डेमोक्रेसी' शब्द का तात्पर्य है:
(A) साम्यवाद का अंतिम चरण।
(B) पश्चिम के मॉडल पर आधारित एक उदार लोकतंत्र।
(C) सर्वहारा वर्ग के नेतृत्व में अर्ध-औपनिवेशिक देशों के लिए एक संक्रमणकालीन चरण।
(D) लेनिन के अधीन सोवियत संघ की राजनीतिक व्यवस्था।

166. "इच्छा, न कि बल, राज्य का आधार है।" यह कथन किसके मूल राजनीतिक दर्शन को सारांशित करता है?
(A) थॉमस हॉब्स
(B) टी.एच. ग्रीन
(C) निकोलो मैकियावेली
(D) कार्ल मार्क्स

167. कौन सा विचारक 'हिंदुत्व' के विचार से सर्वाधिक निकटता से जुड़ा है?
(A) एम.के. गांधी
(B) अरविंदो घोष
(C) बी.आर. अंबेडकर
(D) वी.डी. सावरकर

NODIA

168. सूची I के ग्रीक शब्दों का सूची II के अर्थों के साथ मिलान करें।
सूची I:
P. पोलिस
Q. यूडेमोनिया
R. टेलोस
S. फ्रोनेसिस
सूची II:
1. अंत, उद्देश्य या लक्ष्य
2. नगर-राज्य, एक राजनीतिक समुदाय
3. व्यावहारिक ज्ञान या विवेक
4. अच्छा जीवन, समृद्धि, सुख।
(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-2, Q-4, R-1, S-3
(C) P-2, Q-3, R-1, S-4
(D) P-4, Q-2, R-3, S-1

169. जॉन रॉल्स के सिद्धांत में 'अज्ञानता के पर्दे' की क्या भूमिका है?
(A) यह लोगों को न्याय के सिद्धांतों को समझने से रोकता है।
(B) यह शासक वर्ग के लिए जनता को धोखा देने का एक उपकरण है।
(C) यह सुनिश्चित करता है कि न्याय के सिद्धांत निष्पक्ष रूप से चुने जाएं।
(D) यह एक अन्यायपूर्ण समाज में लोगों की मानसिक स्थिति का वर्णन करता है।

170. रूसो के लिए, सामाजिक अनुबंध में शामिल है:
(A) प्रत्येक सहयोगी और उसके अधिकारों का पूरे समुदाय के प्रति पूर्ण समर्पण।

(B) लोग अपने सभी अधिकार एक पूर्ण संप्रभु को सौंप देते हैं।
(C) लोग सशर्त रूप से कुछ अधिकार एक सीमित सरकार को हस्तांतरित करते हैं।
(D) समाज के सबसे धनी सदस्य अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए सरकार बनाते हैं।

171. शांति पर्व 'दंड' पर बहुत बल देता है क्योंकि:
(A) लोगों को नैतिक बनाने का यही एकमात्र साधन है।
(B) यह राजा के राजस्व का प्राथमिक स्रोत है।
(C) यह क्षेत्रीय विस्तार का एक उपकरण है।
(D) यह धर्मपरायण लोगों की रक्षा करता है और धर्म तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखता है।

172. अंबेडकर की सामाजिक लोकतंत्र की अवधारणा किन सिद्धांतों पर आधारित थी?
(A) जाति, पंथ और धर्म।
(B) स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व।
(C) केंद्रीकरण, अधिकार और आज्ञाकारिता।
(D) परंपरा, रीति-रिवाज और पदानुक्रम।

173. हेगेल की द्वंद्वात्मक पद्धति में किसकी प्रगति शामिल है?
(A) अवलोकन, परिकल्पना, प्रयोग
(B) गुण, मात्रा, माप
(C) वाद, प्रतिवाद, संवाद
(D) होना, शून्यता, बनना

174. 'आधार' और 'अधिरचना' की अवधारणा किसके विचार के केंद्र में है?
(A) जॉन रॉल्स
(B) एंटोनियो ग्राम्शी
(C) जे.एस. मिल
(D) कार्ल मार्क्स

175. एम.एन. रॉय की राजनीतिक यात्रा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. उन्होंने भारत में एक उग्र राष्ट्रवादी के रूप में शुरुआत की।
2. वे अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट आंदोलन में एक प्रमुख व्यक्ति बने।
3. उन्होंने अंततः रेडिकल ह्युमनिज्म का अपना दर्शन विकसित किया।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2, और 3

176. अरस्तू के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा संविधान का विकृत रूप नहीं है?
(A) निरंकुश शासन
(B) पॉलिटी
(C) अल्पतंत्र
(D) लोकतंत्र

177. "ऑन लिबर्टी" में जे.एस. मिल द्वारा व्यक्त 'हानि सिद्धांत' किस पर लागू होता है?
(A) बच्चों और "समाज की पिछड़ी अवस्थाओं" में रहने वाले लोगों सहित सभी मनुष्यों पर।
(B) एक सभ्य समुदाय के स्वस्थ, वयस्क सदस्यों पर।
(C) विभिन्न राष्ट्रों के बीच संबंधों पर।
(D) सरकार के कार्यों पर, लेकिन व्यक्तियों के कार्यों पर नहीं।

178. हॉब्स और लॉक की प्राकृतिक अवस्था के बीच मुख्य अंतर क्या है?
(A) हॉब्स की अवस्था युद्ध की स्थिति है, जबकि लॉक की प्राकृतिक कानून द्वारा शासित और काफी हद तक शांतिपूर्ण है।
(B) हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था में सरकार होती है, जबकि लॉक की अवस्था में नहीं।
(C) हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था में लोगों के पास अधिकार होते हैं, जबकि लॉक की अवस्था में नहीं।
(D) हॉब्स की प्राकृतिक अवस्था ऐतिहासिक है, जबकि लॉक की काल्पनिक है।

179. अभिकथन (A): प्लेटो ने संरक्षक वर्गों के लिए संपत्ति और परिवार के साम्यवाद की प्रणाली की वकालत की।
कारण (R): उनका मानना था कि निजी संपत्ति और पारिवारिक बंधन हितों के टकराव उत्पन्न करेंगे और संरक्षकों को भ्रष्ट कर देंगे।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

180. कौटिल्य के मंडल सिद्धांत का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?
(A) एक राज्य की आदर्श सामाजिक संरचना का वर्णन करना।
(B) राजा की दैवीय उत्पत्ति की व्याख्या करना।
(C) एक राज्य के भीतर प्रशासनिक प्रभागों का विवरण देना।
(D) अंतर-राज्य संबंधों का विश्लेषण करने और विदेश नीति तैयार करने के लिए एक ढांचा प्रदान करना।

181. लेनिन के सिद्धांत में, क्रांति का 'हरावल दस्ता' कौन है?
(A) संपूर्ण सर्वहारा वर्ग
(B) किसान वर्ग
(C) पेशेवर क्रांतिकारियों की एक लघु, अनुशासित दल
(D) बुर्जुआ वर्ग

182. जय प्रकाश नारायण के राजनीतिक विचार में एक प्रमुख विषय क्या था?

Click Here to Buy book on Amazon

(A) एक सुदृढ़, केंद्रीकृत राज्य की आवश्यकता।
(B) विकेंद्रीकृत, दलविहीन लोकतंत्र के आधार पर भारतीय राजनीति का पुनर्निर्माण।
(C) हिंदुत्व की वकालत।
(D) शीत युद्ध में एक सैन्य गुट में सम्मिलित होने का महत्व।

183. ग्राम्शी की 'सबल्टर्न' की अवधारणा किसे संदर्भित करती है?
(A) समाज का शासक वर्ग।
(B) बौद्धिक वर्ग या बुद्धिजीवी।
(C) सैन्य नेतृत्व।
(D) समाज में अधीनस्थ या उत्पीड़ित सामाजिक समूह।

184. जे.एस. मिल द्वारा "बहुमत की निरंकुशता" वाक्यांश का उपयोग किसके खतरों के विरुद्ध चेतावनी देने के लिए किया गया था?
(A) एक लोकतांत्रिक सरकार जहाँ बहुमत अल्पसंख्यकों के अधिकारों और विचारों को दबा सकता है।
(B) एक राजतंत्रीय सरकार।
(C) एक कुलीनतंत्रीय सरकार।
(D) एक विदेशी औपनिवेशिक सरकार।

185. रॉबर्ट नोजिक द्वारा प्रस्तावित न्याय का 'हकदारी सिद्धांत' क्या है?
(A) एक सिद्धांत कि समाज की संपत्ति में प्रत्येक व्यक्ति समान हिस्से का हकदार है।
(B) एक सिद्धांत कि हकदारी को सबसे कम सुविधा प्राप्त लोगों के कल्याण के लिए वितरित किया जाना चाहिए।
(C) एक सिद्धांत कि धारित वस्तुओं में न्याय इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें कैसे प्राप्त और हस्तांतरित किया गया था।
(D) एक सिद्धांत कि राज्य सामाजिक समानता सुनिश्चित करने के लिए धन का पुनर्वितरण करने का हकदार है।

186. निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य के बारे में हेगेल के दृष्टिकोण को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है?
(A) राज्य नैतिक जीवन की उच्चतम प्राप्ति है, जो सार्वभौमिक तर्क का अवतार है।
(B) राज्य एक कृत्रिम संरचना है, अराजकता को रोकने के लिए एक आवश्यक बुराई है।
(C) राज्य वर्ग उत्पीड़न का एक साधन है जिसे अंततः तिरोहित होना चाहिए।
(D) राज्य का एकमात्र वैध कार्य व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करना है।

187. "मेरे शत्रु का शत्रु मेरा मित्र है।" यह सिद्धांत किसका एक प्रमुख घटक है?
(A) प्लेटो का गठबंधन का सिद्धांत।
(B) राजकुमार को मैकियावेली की सलाह।
(C) ग्राम्शी की हेजेमनी की रणनीति।
(D) कौटिल्य का मंडल सिद्धांत।

188. सूची I की पुस्तकों का सूची II के विचारकों के साथ मिलान करें।
सूची I:
P. पॉलिटिक्स
Q. टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट
R. दास कैपिटल
S. द लाइफ डिवाइन
सूची II:
1. जॉन लॉक
2. कार्ल मार्क्स
3. अरविंदो घोष
4. अरस्तू।
(A) P-4, Q-1, R-2, S-3
(B) P-1, Q-4, R-2, S-3
(C) P-4, Q-2, R-1, S-3
(D) P-3, Q-1, R-4, S-2

189. एम.एन. रॉय के अनुसार, रेडिकल ह्युमनिज्म का अंतिम लक्ष्य क्या है?
(A) सर्वहारा वर्ग की तानाशाही स्थापित करना।
(B) एक वैश्विक हिंदू साम्राज्य निर्मित करना।
(C) एक तर्कसंगत और नैतिक समाज के माध्यम से व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुनिश्चित करना।
(D) किसी भी मूल्य पर राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्राप्त करना।

190. अरस्तू के अनुसार क्रांति का मुख्य कारण क्या है?
(A) केवल आर्थिक निर्धनता।
(B) विदेशी आक्रमण और हस्तक्षेप।
(C) शासकों की धार्मिक परंपराओं का पालन करने में विफलता।
(D) जनता द्वारा समानता की या अभिजात वर्ग द्वारा श्रेष्ठता की आकांक्षा।

191. रूसो की 'सामान्य इच्छा' के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. यह अचूक है और सदैव सही होती है।
2. इसे प्रतिनिधियों को सौंपा जा सकता है।
3. यह निजी हितों पर सामान्य हितों को वरीयता देती है।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल 1 और 3
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2, और 3

192. निम्नलिखित में से कौन सा कौटिल्य के 'षाड्गुण्य' के छह तत्वों में से एक नहीं है?
(A) संधि
(B) मित्र
(C) विग्रह
(D) यान

Downloaded from www.pdf.tube

193. उपयोगितावाद का दर्शन, जैसा कि जेरेमी बेंथम द्वारा स्थापित किया गया है, किसका एक रूप है?
(A) कर्तव्यशास्त्र
(B) परिणामवाद
(C) सद्गुण नैतिकता
(D) दैवीय आदेश सिद्धांत

194. प्लेटो के विपरीत, अरस्तू का आदर्श राज्य है:
(A) विधि के शासन और एक सुदृढ़ मध्यम वर्ग द्वारा शासित एक संवैधानिक पॉलिटी।
(B) दार्शनिक-राजाओं द्वारा शासित एक कुलीनतंत्र।
(C) प्लेटो की "लॉज" में वर्णित "द्वितीय सर्वश्रेष्ठ" राज्य।
(D) बिना निजी संपत्ति वाला प्रत्यक्ष लोकतंत्र।

195. गांधी की 'ट्रस्टीशिप' की अवधारणा का तात्पर्य है कि:
(A) राज्य को सभी संपत्ति और उत्पादन के साधनों का स्वामी होना चाहिए।
(B) सभी निजी संपत्ति को समाप्त कर दिया जाना चाहिए।
(C) धनी व्यक्तियों को अपनी अतिरिक्त संपत्ति समाज के लिए न्यास के रूप में रखनी चाहिए।
(D) न्यासियों के एक मंडल को देश पर शासन करना चाहिए।

196. "मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी है।" यह प्रसिद्ध कथन किसके द्वारा दिया गया था?
(A) प्लेटो
(B) हॉब्स
(C) लॉक
(D) अरस्तू

197. निम्नलिखित में से कौन सा विचारक इस कथन का सर्वाधिक समर्थन करेगा: "कराधान जबरन श्रम के समान है"?
(A) जॉन रॉल्स
(B) टी.एच. ग्रीन
(C) रॉबर्ट नोजिक
(D) कार्ल मार्क्स

198. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिन्हें कथन I और कथन II के रूप में अंकित किया गया है।
कथन I: कार्ल मार्क्स के सिद्धांत को अक्सर "वैज्ञानिक समाजवाद" कहा जाता है।
कथन II: मार्क्स ने अपने विश्लेषण को इतिहास की भौतिकवादी अवधारणा और पूंजीवादी उत्पादन की आलोचना पर आधारित करके काल्पनिक समाजवादियों से पृथक करने का प्रयास किया।
उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
(D) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।

199. निम्नलिखित में से किसने राज्य को अपूरणीय वर्ग विरोधों के परिणाम के रूप में देखा?
(A) टी.एच. ग्रीन
(B) जॉन लॉक
(C) जी.डब्ल्यू.एफ. हेगेल
(D) वी.आई. लेनिन

200. शांति पर्व में राजा के आचरण के लिए 'पंचशील' की अवधारणा विदेश नीति के आधुनिक 'पंचशील' से भिन्न है। प्राचीन अवधारणा में किसके लिए सिद्धांत सम्मिलित थे?
(A) व्यक्तिगत नैतिक आचरण और आत्म-नियंत्रण।
(B) गैर-हस्तक्षेप पर आधारित अंतर-राज्य संबंध।
(C) आर्थिक और व्यापार समझौते।
(D) राजा की परिषद में पांच प्रमुख मंत्रालय।

NODIA

201. अभिकथन (A): टी.एच. ग्रीन के लिए, स्वतंत्रता का अर्थ केवल नियंत्रण की अनुपस्थिति नहीं है।
कारण (R): वास्तविक स्वतंत्रता आत्म-साक्षात्कार के लिए कार्य करने की एक सकारात्मक क्षमता है, और राज्य निर्धनता तथा अज्ञानता जैसी बाधाओं को दूर करके इसे बढ़ावा दे सकता है।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

202. नारा "दुनिया के मजदूरों, एक हो जाओ!" प्रसिद्ध रूप से किसके साथ जुड़ा हुआ है?
(A) मार्क्स और एंगेल्स
(B) लेनिन और माओ
(C) बेंथम और मिल
(D) प्लेटो और अरस्तू

203. निम्नलिखित में से कौन सा 'समुदायवादी' राजनीतिक सिद्धांत का सबसे उपयुक्त विवरण है?
(A) एक सिद्धांत जो सामान्य हित पर व्यक्तिगत अधिकारों को प्राथमिकता देता है।
(B) एक सिद्धांत जो राज्य के पूर्ण उन्मूलन की वकालत करता है।
(C) एक सिद्धांत जो समाज में कुल उपयोगिता को अधिकतम करना चाहता है।
(D) एक सिद्धांत जो उन सामाजिक संदर्भों पर बल देता है जो पहचान को आकार देते हैं।

204. कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, 'वार्ता' चार आवश्यक विद्याओं में से एक है, जो संदर्भित करती है:
(A) दर्शन और तर्कशास्त्र को
(B) अर्थशास्त्र के विज्ञान को
(C) वेदों और धार्मिक शास्त्रों को
(D) शासन और दंड के विज्ञान को

205. मैकियावेली के लिए, एक राजकुमार की प्राथमिक चिंता होनी चाहिए:
(A) अपनी आत्मा का उद्धार।
(B) अपनी प्रजा का आर्थिक कल्याण।
(C) शक्ति का अर्जन और संरक्षण।
(D) न्याय और निष्पक्षता की खोज।

206. किस विचारक ने तर्क दिया कि प्राकृतिक अवस्था में जीवन "एकाकी, निर्धन, घृणित, पाशविक और अल्प" है?
(A) जॉन लॉक
(B) ज्यां-जैक रूसो
(C) अरस्तू
(D) थॉमस हॉब्स

207. अंबेडकर के अनुसार, पूना पैक्ट में मुख्य दोष क्या था?
(A) संयुक्त निर्वाचक मंडल बहुमत के अधीन प्रतिनिधियों को चुन सकते हैं।
(B) इसने दलित वर्गों को अत्यधिक सीटें प्रदान कीं।
(C) इसने सीटों के आरक्षण को पूर्णतः समाप्त कर दिया।
(D) इस पर महात्मा गांधी की सहमति के बिना हस्ताक्षर किए गए थे।

208. हेगेल के इतिहास के दर्शन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. इतिहास स्वतंत्रता की प्रगतिशील प्राप्ति है।
2. राज्य पृथ्वी पर इस स्वतंत्रता का अंतिम अवतार है।
3. इतिहास की प्रक्रिया अराजक है और किसी भी तर्कसंगत स्वरूप से रहित है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2, और 3

209. 'सांस्कृतिक क्रांति' की अवधारणा किसके साथ सर्वाधिक निकटता से जुड़ी हुई है?
(A) लेनिन
(B) माओ
(C) ग्राम्शी
(D) मार्क्स

210. यह सिद्धांत कि न्याय की आवश्यकता है कि "सामाजिक और आर्थिक असमानताएँ सबसे कम सुविधा प्राप्त लोगों के अधिकतम लाभ के लिए हों", किस रूप में जाना जाता है?
(A) भेद का सिद्धांत
(B) उपयोगिता का सिद्धांत
(C) हानि का सिद्धांत
(D) हकदारी का सिद्धांत

211. अरविंदो की "द लाइफ डिवाइन" का केंद्रीय विषय क्या है?
(A) भारत की स्वतंत्रता के लिए एक राजनीतिक कार्यक्रम।
(B) पश्चिमी भौतिकवाद की आलोचना।
(C) पदार्थ से अतिमानस तक आध्यात्मिक विकास का एक सिद्धांत।
(D) भगवद गीता पर एक टिप्पणी।

212. सूची I के सामाजिक अनुबंध विचारकों का सूची II में संप्रभुता की प्रकृति के साथ मिलान करें।
सूची I:
P. हॉब्स
Q. लॉक
R. रूसो
सूची II:
1. सीमित, न्यास पर आधारित और उत्तरदायी
2. पूर्ण, अविभाज्य और अक्षुण्ण
3. सामान्य इच्छा, जो अक्षुण्ण और अविभाज्य है।
(A) P-1, Q-2, R-3
(B) P-2, Q-3, R-1
(C) P-3, Q-1, R-2
(D) P-2, Q-1, R-3

213. "दार्शनिकों ने केवल विभिन्न माध्यमों से विश्व की व्याख्या की है; मुख्य बिंदु इसे बदलना है।" यह प्रसिद्ध शोध किसका है?
(A) जी.डब्ल्यू.एफ. हेगेल
(B) जॉन रॉल्स
(C) कार्ल मार्क्स
(D) जे.एस. मिल

214. अरविंदो घोष द्वारा 'निष्क्रिय प्रतिरोध' की अवधारणा गांधीवादी 'सत्याग्रह' से किस प्रकार भिन्न थी?
(A) अरविंदो की पद्धति विशुद्ध रूप से आध्यात्मिक शक्ति पर आधारित थी।
(B) यदि निष्क्रिय प्रतिरोध विफल हो जाए तो अरविंदो ने हिंसा के उपयोग को एक वैध विकल्प के रूप में स्वीकार किया था।
(C) अरविंदो की पद्धति केवल आर्थिक बहिष्कार के लिए थी।
(D) गांधी की पद्धति में सक्रिय सविनय अवज्ञा सम्मिलित थी, जिसे अरविंदो ने अस्वीकृत कर दिया था।

215. हॉब्स के अनुसार संप्रभुता की मूलभूत विशेषता क्या है?
(A) यह संवैधानिक कानून द्वारा सीमित है।
(B) यह सरकार की विभिन्न शाखाओं के बीच विभाज्य है।
(C) यह शासितों की सहमति पर आधारित है और इसे निरस्त किया जा सकता है।
(D) यह पूर्ण और अविभाज्य है।

216. कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में 'प्रकृति' शब्द किसे संदर्भित करता है?
(A) राज्य के तत्वों या अंगों को।
(B) प्राकृतिक अवस्था को।
(C) राजा की मंत्रिपरिषद को।

Click Here to Buy book on Amazon

(D) कराधान की प्रणाली को।

217. अरस्तू की दृष्टि में, 'पॉलिटि' 'लोकतंत्र' की तुलना में श्रेष्ठ व्यावहारिक संविधान क्यों है?
(A) पॉलिटि पर गुणी कुछ लोगों का शासन होता है, जबकि लोकतंत्र भीड़ का शासन है।
(B) पॉलिटि राजतंत्र का दूसरा नाम है, जो सरकार का सर्वाधिक कुशल रूप है।
(C) पॉलिटि एक मिश्रित संविधान है जो धनी और निर्धन के हितों को संतुलित करता है।
(D) पॉलिटि एक दार्शनिक-राजा की अनुमति देता है, जबकि लोकतंत्र नहीं।

218. "एनार्की, State, और Utopia" के लेखक कौन हैं?
(A) रॉबर्ट नोजिक
(B) जॉन रॉल्स
(C) माइकल सैंडेल
(D) चार्ल्स टेलर

219. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिन्हें कथन I और कथन II के रूप में अंकित किया गया है।
कथन I: मैकियावेली के अनुसार, एक राजकुमार को प्रेम किए जाने की तुलना में डरा हुआ अधिक होना चाहिए।
कथन II: प्रेम की तुलना में भय एक अधिक विश्वसनीय आवेग है, क्योंकि इसे दंड के भय से बनाए रखा जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
(D) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।

220. एम.के. गांधी की "हिंद स्वराज" का प्राथमिक लक्ष्य क्या था?
(A) स्वतंत्र भारत के लिए एक विस्तृत संविधान प्रदान करना।
(B) आधुनिक, औद्योगिक, भौतिकवादी सभ्यता की मौलिक आलोचना करना।
(C) समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाने के लिए तर्क देना।
(D) अंग्रेजों को पराजित करने के लिए सैन्य रणनीति की रूपरेखा तैयार करना।

221. सावरकर की हिंदू की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य घटक नहीं है?
(A) भारत को अपनी पितृभूमि मानना।
(B) भारत को अपनी पुण्यभूमि मानना।
(C) किसी विशिष्ट हठधर्मिता या आस्तिक विश्वास का पालन करना।
(D) एक साझा जातीय पूर्वज साझा करना।

222. लेनिन की "इम्पीरियलिज्म, द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म" तर्क देती है कि:
(A) साम्राज्यवाद सैन्यवादी राज्यों द्वारा चयनित एक नीति है।
(B) साम्राज्यवाद उपनिवेशवादी और उपनिवेशित दोनों को लाभ पहुँचाता है।
(C) साम्राज्यवाद एक क्षणिक चरण है जिसे मुक्त व्यापार द्वारा समाप्त किया जाएगा।
(D) साम्राज्यवाद एकाधिकार पूंजीवाद के लिए एक आर्थिक आवश्यकता है।

223. 'मूल स्थिति' किसके सिद्धांत में 'अज्ञानता के पर्दे' द्वारा पहचानी जाने वाली एक काल्पनिक स्थिति है?
(A) जॉन रॉल्स
(B) रॉबर्ट नोजिक
(C) कार्ल मार्क्स
(D) एंटोनियो ग्राम्शी

NODIA

224. स्वतंत्रता पर जे.एस. मिल के विचारों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. उन्होंने विचार और अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता की वकालत की।
2. उनका मानना था कि राज्य 'स्व-विषयक' कार्यों में हस्तक्षेप कर सकता है।
3. उन्होंने मानव प्रगति के लिए इसकी उपयोगिता के आधार पर स्वतंत्रता का औचित्य सिद्ध किया।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2, और 3

225. "चेतना जीवन को निर्धारित नहीं करती, बल्कि जीवन चेतना को निर्धारित करता है।" यह कथन किसके सिद्धांत को समाहित करता है?
(A) हेगेलियन आदर्शवाद
(B) मार्क्सवादी ऐतिहासिक भौतिकवाद
(C) लॉकियन अनुभववाद
(D) प्लेटोनिक आकारवाद

226. लॉक के अनुसार, मनुष्यों के राष्ट्रमंडल में एकीकृत होने का मुख्य कारण क्या है?
(A) अपने जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के पारस्परिक संरक्षण के लिए।
(B) पाशविक प्राकृतिक अवस्था से बचने के लिए।
(C) आध्यात्मिक उद्धार प्राप्त करने के लिए।
(D) एक ऐसे संप्रभु को निर्मित करने के लिए जो उनके लिए समस्त निर्णय लेगा।

227. अभिकथन (A): रूसो का तर्क है कि संप्रभुता का प्रतिनिधित्व नहीं किया जा सकता।
कारण (R): सामान्य इच्छा, जो संप्रभुता का सार है, को दूसरों को हस्तांतरित या सौंपा नहीं जा सकता; इसे नागरिकों द्वारा स्वयं प्रत्यक्ष रूप से व्यक्त किया जाना चाहिए।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।

(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

228. विचारधारा के माध्यम से सहमतिपूर्ण शासन का विचार ग्राम्शी की किस अवधारणा के केंद्र में है?
(A) गति का युद्ध
(B) निष्क्रिय क्रांति
(C) जैविक संकट
(D) हेजेमनी

229. "द सबजेक्शन ऑफ विमेन" के लेखक हैं:
(A) जेरेमी बेंथम
(B) जॉन लॉक
(C) जे.एस. मिल
(D) मैरी वोलस्टोनक्राफ्ट

230. अरस्तू के लिए, परिवार है:
(A) एक कृत्रिम संस्था जिसे शासक वर्ग के लिए समाप्त कर दिया जाना चाहिए।
(B) राज्य की एक प्राकृतिक और आवश्यक इकाई, जो प्रजनन और दैनिक आवश्यकताओं के लिए अनिवार्य है।
(C) पोलिस के राजनीतिक जीवन से कोई संबंध न रखने वाला एक निजी क्षेत्र।
(D) संघर्ष और वैमनस्य का स्रोत जो राज्य को संकट में डालता है।

231. शांति पर्व में, भीष्म किसे 'राजधर्म' के सिद्धांतों पर निर्देश दे रहे हैं?
(A) धृतराष्ट्र
(B) दुर्योधन
(C) अर्जुन
(D) युधिष्ठिर

232. प्लेटो के रिपब्लिक में "पत्नियों और संपत्ति के साम्यवाद" का मुख्य उद्देश्य क्या है?
(A) संरक्षकों और सहायकों के बीच एकता को बढ़ावा देना और निजी हितों को समाप्त करना।
(B) यह सुनिश्चित करना कि राज्य में प्रत्येक व्यक्ति समान है।
(C) उत्पादक वर्ग को भौतिक अभावों से मुक्त करना।
(D) पूरी जनसंख्या के लिए सुजननिकी की एक प्रणाली बनाना।

233. निम्नलिखित में से कौन रॉबर्ट नोजिक के हकदारी सिद्धांत के सिद्धांतों में से एक नहीं है?
(A) धारित वस्तुओं के मूल अधिग्रहण में न्याय।
(B) धारित वस्तुओं के हस्तांतरण में न्याय।
(C) धारित वस्तुओं के स्वरूपित वितरण का सिद्धांत।
(D) धारित वस्तुओं में अन्याय का सुधार।

234. सूची I के शब्दों का सूची II के विचारकों के साथ मिलान करें।
सूची I:
P. फेलिसिफिक कैलकुलस
Q. निरपेक्ष आदेश
R. भेद का सिद्धांत
S. सामान्य इच्छा
सूची II:
1. जॉन रॉल्स
2. ज्यां-जैक रूसो
3. इमैनुएल कांट
4. जेरेमी बेंथम।
(A) P-4, Q-3, R-1, S-2
(B) P-1, Q-2, R-3, S-4
(C) P-4, Q-1, R-2, S-3
(D) P-2, Q-3, R-1, S-4

235. एम.एन. रॉय का राजनीतिक दर्शन किसमें समाप्त हुआ?
(A) रूढ़िवादी मार्क्सवाद
(B) अराजकतावादी-सिंडिकलिज्म
(C) गांधीवादी सर्वोदय
(D) रेडिकल या नव मानवतावाद

236. टी.एच. ग्रीन के लिए, राजनीतिक दायित्व का आधार क्या है?
(A) संप्रभु की दमनकारी शक्ति।
(B) समुदाय की सामान्य इच्छा, जो राज्य में अभिव्यक्ति पाती है क्योंकि यह सामान्य हित को बनाए रखती है।
(C) राजाओं का दैवीय अधिकार।
(D) एक ऐतिहासिक सामाजिक अनुबंध।

237. 'नाइट-वॉचमैन के रूप में न्यूनतम राज्य' का विचार किसके राजनीतिक दर्शन का केंद्र है?
(A) टी.एच. ग्रीन
(B) जॉन रॉल्स
(C) रॉबर्ट नोजिक
(D) कार्ल मार्क्स

238. जय प्रकाश नारायण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. वे अपने शुरुआती वर्षों में मार्क्सवादी थे।
2. वे बाद में गांधीवादी बन गए और सर्वोदय की वकालत की।
3. उन्होंने 1970 के दशक में 'सम्पूर्ण क्रांति' का आह्वान किया।
उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2, और 3

239. 'गति के युद्ध' और 'स्थिति के युद्ध' के बीच अंतर किसके द्वारा किया गया था?

Downloaded from www.pdf.tube

(A) एंटोनियो ग्राम्शी
(B) वी.आई. लेनिन
(C) माओ जेदोंग
(D) कार्ल मार्क्स

240. गांधी के 'स्वराज' के विचार का सबसे उपयुक्त विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है?
(A) ब्रिटिश शासन से राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करना।
(B) स्वयं पर शासन, या आत्म-नियंत्रण, जो सच्ची स्वतंत्रता की कुंजी है।
(C) भारत के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता।
(D) एक हिंदू राष्ट्र की स्थापना।

241. अभिकथन (A): मार्क्स ने भविष्यवाणी की थी कि सर्वहारा क्रांति सर्वप्रथम ब्रिटेन और जर्मनी जैसे सर्वाधिक उन्नत पूंजीवादी देशों में होगी।
कारण (R): उनका मानना था कि पूंजीवाद के आंतरिक अंतर्विरोध इन देशों में सर्वाधिक विकसित होंगे।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

242. कौटिल्य के अनुसार, राजा का अधिकार किसके द्वारा सर्वाधिक बना रहता है?
(A) लोगों का कल्याण और सुरक्षा सुनिश्चित करने से प्राप्त जन-समर्थन द्वारा।
(B) केवल दैवीय स्वीकृति द्वारा।
(C) एक शक्तिशाली, वंशानुगत कुलीन वर्ग की निष्ठा द्वारा।
(D) निरंतर, आक्रामक युद्ध की नीति द्वारा।

243. 'सन्निहित स्व' की अवधारणा किसका एक केंद्रीय विषय है?
(A) उदारवाद
(B) उदारतावाद
(C) समुदायवाद
(D) उपयोगितावाद

244. हेगेल के दर्शन को सबसे अच्छी तरह से वर्णित किया गया है:
(A) भौतिकवाद
(B) अनुभववाद
(C) अस्तित्ववाद
(D) आदर्शवाद

245. लॉक के राजनीतिक सिद्धांत में, क्या होता है यदि सरकार लोगों द्वारा उसमें रखे गए विश्वास का उल्लंघन करती है?
(A) लोगों को निष्क्रिय रूप से आज्ञा माननी चाहिए।
(B) लोगों को उच्च अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अपील करनी चाहिए।
(C) सरकार भंग हो जाती है और लोगों को एक नई सरकार स्थापित करने का अधिकार होता है।
(D) प्राकृतिक अवस्था वापस आ जाती है।

246. अंबेडकर के अनुसार, जाति व्यवस्था केवल श्रम का विभाजन नहीं है बल्कि यह है:
(A) कुशल आर्थिक उत्पादन के लिए एक प्रणाली।
(B) श्रमिकों का विभाजन।
(C) प्राकृतिक और हितकारी सामाजिक पदानुक्रम।
(D) सामाजिक गतिशीलता की एक लचीली प्रणाली।

247. मैकियावेली के लिए, एक राजकुमार के लिए सबसे सुरक्षित है:
(A) प्रेम किया जाना
(B) उदार होना
(C) घृणा किया जाना
(D) डरा हुआ होना

NODIA

248. बेंथम और मिल के उपयोगितावाद के बीच मुख्य अंतर यह है कि:
(A) बेंथम केवल सुख की मात्रा पर विचार करते हैं, जबकि मिल गुणवत्ता पर भी विचार करते हैं।
(B) बेंथम एक लोकतांत्रिक थे, जबकि मिल एक राजतंत्रवादी थे।
(C) बेंथम ने सरकारी हस्तक्षेप का समर्थन किया, जबकि मिल ने मुक्त बाजार की वकालत की।
(D) बेंथम ने सुख पर ध्यान केंद्रित किया, जबकि मिल ने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित किया।

249. "साम्राज्यवाद पूंजीवाद का एकाधिकार चरण है।" यह किसकी कृति का केंद्रीय शोध है:
(A) कार्ल मार्क्स
(B) माओ जेदोंग
(C) वी. आई. लेनिन
(D) एंटोनियो ग्राम्शी

250. 'निष्पक्षता के रूप में न्याय' किसके राजनीतिक दर्शन की आधारशिला है?
(A) जॉन रॉल्स
(B) रॉबर्ट नोज़िक
(C) जेरेमी बेंथम
(D) माइकल सैंडेल

251. निम्नलिखित में से कौन कौटिल्य सहित प्राचीन भारतीय विचार में वर्णित चार 'उपायों' में से एक नहीं है?
(A) साम
(B) दाम
(C) भेद
(D) युद्ध

252. अरस्तू के राजनीतिक विचार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. उन्होंने दासता की संस्था का समर्थन किया।

2. उनका मानना था कि राज्य एक प्राकृतिक संरचना है।
3. उन्होंने सरकार के सबसे स्थिर रूप के रूप में एक मिश्रित संविधान की वकालत की।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2, और 3

253. यह विचार कि एक अर्ध-औपनिवेशिक देश में क्रांति को ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों को घेरकर आगे बढ़ना चाहिए, किसका एक प्रमुख रणनीतिक योगदान है:
(A) वी.आई. लेनिन
(B) कार्ल मार्क्स
(C) माओ जेदोंग
(D) एंटोनियो ग्राम्शी

254. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिन्हें कथन I और कथन II के रूप में अंकित किया गया है।
कथन I: टी.एच. ग्रीन को सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक माना जाता है।
कथन II: उन्होंने तर्क दिया कि वास्तविक स्वतंत्रता के लिए न केवल कानूनी बल की अनुपस्थिति आवश्यक है, बल्कि कार्य करने की क्षमता भी आवश्यक है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
(D) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।

255. जय प्रकाश नारायण द्वारा समर्थित 'सम्पूर्ण क्रांति' की अवधारणा थी:
(A) व्यापक सामाजिक, राजनीतिक और नैतिक परिवर्तन के लिए एक कार्यक्रम।
(B) सरकार को हिंसक रूप से उखाड़ फेंकने का आह्वान।
(C) तीव्र औद्योगिकीकरण की योजना।
(D) एक पृथक राज्य के निर्माण के लिए एक आंदोलन।

256. प्लेटो के लिए, आदर्श राज्य किसके द्वारा शासित होता है?
(A) नागरिकों के बहुमत द्वारा।
(B) दार्शनिक-राजाओं द्वारा।
(C) सर्वाधिक धनी वर्ग द्वारा।
(D) सैन्य नेताओं द्वारा।

257. किस विचारक ने तर्क दिया कि सामान्य इच्छा सदैव सही होती है, लेकिन जो निर्णय उसका मार्गदर्शन करता है वह सदैव प्रबुद्ध नहीं होता?
(A) हॉब्स
(B) रूसो
(C) लॉक
(D) बेंथम

258. कार्ल मार्क्स की 'वर्ग संघर्ष' की अवधारणा किसके बीच अंतर्निहित संघर्ष को संदर्भित करती है?
(A) उत्पादन के साधनों के स्वामियों और संपत्तिहीन श्रमिकों के बीच।
(B) विभिन्न राष्ट्रों के बीच।
(C) विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच।
(D) राज्य और व्यक्ति के बीच।

259. राज्य के 'सप्तांग सिद्धांत' किसमें पाया जाता है?
(A) द रिपब्लिक और पॉलिटिक्स
(B) द प्रिंस और लेविआथन
(C) शांति पर्व और अर्थशास्त्र
(D) वेद और उपनिषद

260. अपने बाद के चरण में, एम.एन. रॉय किसके आलोचक थे?
(A) केवल संसदीय लोकतंत्र के।
(B) केवल साम्यवाद के।
(C) केवल राजतंत्रीय शासन के।
(D) संसदीय लोकतंत्र और साम्यवाद दोनों के।

261. अभिकथन (A): समुदायवादी विचारक व्यक्तिगत अधिकारों पर उदारवादी बल की आलोचना करते हैं।
कारण (R): उनका तर्क है कि परमाणुवादी व्यक्ति पर उदारवादी ध्यान इस बात की उपेक्षा करता है कि लोग अपने समुदायों और साझा परंपराओं द्वारा गठित होते हैं।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

262. सूची I के भारतीय विचारकों का सूची II के प्रमुख विचारों के साथ मिलान करें।
सूची I:
P. गांधी
Q. अंबेडकर
R. सावरकर
S. एम.एन. रॉय
सूची II:
1. हिंदुत्व
2. रेडिकल ह्युमनिज्म
3. जाति का विनाश
4. ट्रस्टीशिप।
(A) P-4, Q-3, R-1, S-2
(B) P-3, Q-4, R-1, S-2
(C) P-4, Q-1, R-3, S-2
(D) P-2, Q-3, R-1, S-4

263. जे.एस. मिल का कार्य मुख्य रूप से किसके बचाव पर केंद्रित है?
(A) प्राचीन स्वतंत्रता

Click Here to Buy book on Amazon

(B) दोनों का संश्लेषण
(C) केवल आर्थिक स्वतंत्रता
(D) आधुनिक स्वतंत्रता

264. निम्नलिखित में से किसने तर्क दिया कि संपत्ति एक प्राकृतिक अधिकार है जो प्रकृति के साथ अपने श्रम को सम्मिलित करने से प्राप्त होता है?
(A) जॉन लॉक
(B) थॉमस हॉब्स
(C) कार्ल मार्क्स
(D) ज्यां-जैक रूसो

265. निम्नलिखित विचारकों का सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है?
1. मैकियावेली
2. अरस्तू
3. लॉक
4. मार्क्स।
(A) 2, 1, 3, 4
(B) 1, 2, 3, 4
(C) 2, 3, 1, 4
(D) 1, 3, 2, 4

266. निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सावरकर की हिंदुत्व की अवधारणा के लिए केंद्रीय है लेकिन हिंदू धर्म का पालन करने वाले के लिए अनिवार्य नहीं है?
(A) भारत को अपनी पुण्यभूमि मानना।
(B) वेदों के प्रामाण्य में विश्वास।
(C) विशिष्ट देवताओं की पूजा।
(D) कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास।

267. कथन "राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है" किससे संबंधित है:
(A) मार्क्स
(B) ग्रीन
(C) बेंथम
(D) हेगेल

268. ग्राम्शी के अनुसार, शासक वर्ग अपना प्रभुत्व कैसे बनाए रखता है?
(A) केवल बल और विवशता के माध्यम से।
(B) बल और सहमति के संयोजन के माध्यम से।
(C) केवल लोकतांत्रिक चुनावों के माध्यम से।
(D) केवल आर्थिक प्रोत्साहनों के माध्यम से।

269. प्लेटो के रिपब्लिक में 'धातुओं का मिथक' का मुख्य उद्देश्य क्या है?
(A) एथेंस की विद्यमान वर्ग संरचना को उचित ठहराना।
(B) सुजननिकी के लिए एक वैज्ञानिक आधार प्रदान करना।
(C) नागरिकों को अपना स्थान स्वीकार करने और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए सहमत करना।
(D) धन और व्यापार की उत्पत्ति की व्याख्या करना।

270. हॉब्स के सामाजिक अनुबंध के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. यह लोगों द्वारा आपस में किया गया एक अनुबंध है।
2. संप्रभु अनुबंध का एक पक्षकार है।
3. यदि प्रजा के जीवन को संकट हो तो वे संप्रभु का विरोध करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
(A) केवल 1 और 3
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 2
(D) 1, 2 और 3

271. अरविंदो के अनुसार, राष्ट्रीय जागरण के तीन चरण हैं:
(A) आत्म-खोज की अवधि, कार्रवाई की अवधि और आत्म-साक्षात्कार की अवधि।
(B) याचिका, विरोध और विद्रोह।
(C) पुनरुत्थान, पुनर्निर्माण और आध्यात्मिक बोध।
(D) बहिष्कार, स्वदेशी और निष्क्रिय प्रतिरोध।

272. रॉल्स के न्याय के सिद्धांत में, किस सिद्धांत को अन्यों पर शब्दकोशीय वरीयता प्राप्त है?
(A) भेद का सिद्धांत।
(B) समान बुनियादी स्वतंत्रता का सिद्धांत।
(C) अवसर की उचित समानता का सिद्धांत।
(D) उपयोगिता का सिद्धांत।

273. मार्क्स के शुरुआती लेखों में 'अलगाव' की अवधारणा निम्नलिखित में से किसे छोड़कर कार्यकर्ता के अलगाव को संदर्भित करती है:
(A) उसके श्रम के उत्पाद से।
(B) उसकी राष्ट्रीय पहचान से।
(C) उत्पादन के कार्य से।
(D) उसके 'प्रजाति-सत्व' या मानवीय सार से।

274. निम्नलिखित में से कौन सामाजिक अनुबंध सिद्धांतकार नहीं है?
(A) जेरेमी बेंथम
(B) थॉमस हॉब्स
(C) जॉन लॉक
(D) ज्यां-जैक रूसो

275. अरस्तू के अनुसार, दासता है:
(A) सदैव अन्यायपूर्ण और इसे समाप्त किया जाना चाहिए।
(B) केवल युद्धबंदियों के लिए उचित।
(C) प्राकृतिक दास और स्वामी दोनों के लिए स्वाभाविक और हितकारी।
(D) बिना किसी नैतिक निहितार्थ वाली एक आर्थिक व्यवस्था।

276. नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिन्हें कथन I और कथन II के रूप में अंकित किया गया है।

NODIA

कथन I: लेनिन ने मार्क्स के क्रांति के सिद्धांत को यह तर्क देकर संशोधित किया कि यह पूंजीवादी श्रृंखला की एक 'दुर्बल कड़ी' में हो सकती है।
कथन II: रूस, एक अर्ध-सामंती और औद्योगिक रूप से पिछड़ा देश होने के नाते, लेनिन के सैद्धांतिक नवाचार के लिए संदर्भ प्रदान करता था। उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
(D) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।

277. प्राचीन भारतीय विचार के अनुसार वे 'छह शत्रु' कौन से हैं जिन पर एक राजा को विजय प्राप्त करनी चाहिए?
(A) निर्धनता, रोग, अकाल, बाढ़, अग्नि और महामारी।
(B) पड़ोसी राज्य, पीछे का राज्य, मध्यम राजा, तटस्थ राजा, सहयोगी और शत्रु का सहयोगी।
(C) काम, क्रोध, लोभ, मान, मद और हर्ष।
(D) पाखंड, नास्तिकता, विदेशी संस्कृति, अवज्ञा, अनादर और विश्वासघात।

278. निम्नलिखित में से कौन सा रूसो के विज्ञान और कला पर दृष्टिकोण का सबसे अच्छा वर्णन करता है?
(A) वे मानवीय प्रगति और सुख के प्राथमिक चालक हैं।
(B) उन्होंने मानवीय नैतिकता को भ्रष्ट किया है और असमानता को जन्म दिया है।
(C) वे तटस्थ शक्तियां हैं जिनका नैतिकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
(D) सामान्य इच्छा की सेवा के लिए उन्हें राज्य द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए।

279. शांति पर्व किन विषयों का अन्वेषण करता है?
(A) विशेष रूप से युद्ध की कला और सैन्य रणनीति।
(B) नल और दमयन्ती की प्रेम कथा।
(C) युद्ध के मैदान में कृष्ण और अर्जुन के बीच दार्शनिक संवाद।
(D) राजा के कर्तव्य, शासन और मोक्ष का मार्ग।

280. जे.एस. मिल के लिए, सरकार का सर्वोत्तम रूप है:
(A) प्रतिनिधि सरकार
(B) पूर्ण राजतंत्र
(C) कुलीनतंत्र
(D) प्रत्यक्ष लोकतंत्र

281. सूची I के शब्दों का सूची II के अर्थों के साथ मिलान करें।
सूची I:
P. हेजेमनी
Q. नागरिक समाज
R. स्थिति का युद्ध
S. जैविक बुद्धिजीवी
सूची II:
1. एक विचारक जो उभरते वर्ग के हितों को स्पष्ट करता है
2. निजी संस्थानों का क्षेत्र जहाँ सहमति निर्मित की जाती है
3. प्रमुख विचारधारा को दुर्बल करने के लिए दीर्घकालिक संघर्ष
4. सहमति और नैतिक-बौद्धिक अधिकार पर आधारित नेतृत्व।
(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-4, Q-2, R-3, S-1
(C) P-4, Q-3, R-2, S-1
(D) P-2, Q-4, R-1, S-3

282. 'प्राकृतिक अवस्था' सामाजिक अनुबंध सिद्धांतकारों द्वारा किसलिए उपयोग की गई एक काल्पनिक अवधारणा है:
(A) राजनीतिक अधिकार के उद्देश्य और औचित्य की व्याख्या करना।
(B) एक काल्पनिक भविष्य के समाज का वर्णन करना।
(C) आदिम समाजों में आर्थिक संबंधों का विश्लेषण करना।
(D) राजाओं के दैवीय अधिकार को उचित ठहराना।

283. निम्नलिखित में से कौन इस कथन के लिए प्रसिद्ध है, "जो वास्तविक है वह तर्कसंगत है और जो तर्कसंगत है वह वास्तविक है"?
(A) जे.एस. मिल
(B) कार्ल मार्क्स
(C) इमैनुएल कांट
(D) जी.डब्ल्यू.एफ. हेगेल

284. निम्नलिखित विचारकों पर विचार करें:
1. जॉन रॉल्स
2. रॉबर्ट नोजिक
3. माइकल वाल्ज़र
उपरोक्त में से किसने तर्क दिया कि न्याय के सिद्धांत विशिष्ट सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों के सापेक्ष हैं?
(A) केवल 1
(B) केवल 2
(C) केवल 3
(D) 1 और 2

285. पूंजीवाद के अपने विश्लेषण में, मार्क्स ने 'वस्तु पूजा' को किस रूप में पहचाना:
(A) उपभोक्ताओं की अधिक वस्तुएं क्रय करने की अत्यधिक आकांक्षा।
(B) विज्ञापन में धार्मिक प्रतीकों का उपयोग।
(C) व्यक्तियों के बीच सामाजिक संबंधों को वस्तुओं के बीच संबंधों के रूप में देखना।
(D) लाभ संचय के प्रति पूंजीपति का जुनून।

286. कौटिल्य के राजनीतिक विचार और प्लेटो के राजनीतिक विचार के बीच मूलभूत अंतर क्या है?
(A) कौटिल्य लोकतंत्र की वकालत करते हैं, जबकि प्लेटो राजतंत्र की वकालत करते हैं।
(B) कौटिल्य का राज्य लघु और आत्मनिर्भर है, जबकि प्लेटो

NODIA

का एक विशाल साम्राज्य है।
(C) कौटिल्य नैतिकता को राजनीति से पृथक करते हैं, जबकि प्लेटो ऐसा नहीं करते।
(D) कौटिल्य शासन-कला पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि प्लेटो न्याय और नैतिकता पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

287. निम्नलिखित में से कौन सा गांधी के आदर्श राज्य, 'राम राज्य' की विशेषता नहीं है?
(A) इसका तात्पर्य एक अत्यधिक केंद्रीकृत और शक्तिशाली सरकार है।
(B) यह पृथ्वी पर ईश्वर का राज्य है।
(C) यह सत्य और अहिंसा पर आधारित है।
(D) यह शुद्ध नैतिक अधिकार पर आधारित जनता की संप्रभुता का प्रतीक है।

288. लेनिन के अनुसार 'राज्य' है:
(A) सामाजिक संघर्षों का एक तटस्थ मध्यस्थ।
(B) एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के दमन का एक साधन।
(C) नैतिक जीवन की उच्चतम अभिव्यक्ति।
(D) एक निकाय जो सभी नागरिकों के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करता है।

289. टी.एच. ग्रीन द्वारा व्यक्त 'सकारात्मक स्वतंत्रता' का मूल विचार है:
(A) सभी बाहरी बाधाओं से मुक्ति।
(B) दूसरों के साथ मिलकर आत्म-साक्षात्कार के लिए कार्य करने की शक्ति।
(C) राजनीतिक जीवन में भाग लेने की क्षमता।
(D) असीमित संपत्ति संचित करने का अधिकार।

290. निम्नलिखित में से किसने 'द प्रिंस' और 'द डिस्कोर्स' के बीच स्पष्ट अंतर किया?
(A) मैकियावेली
(B) अरस्तू
(C) हॉब्स
(D) लॉक

291. अभिकथन (A): एम.एन. रॉय के रेडिकल ह्युमनिज्म में, 'तर्क' एक केंद्रीय तत्व है।
कारण (R): रॉय का मानना था कि मनुष्य स्वाभाविक रूप से तर्कसंगत है और यही तर्कसंगतता उसे अलौकिक स्वीकृति के बिना नैतिक होने की अनुमति देती है।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

292. रॉल्सियन उदारवाद के विरुद्ध समुदायवादी विचारधारा का मुख्य तर्क यह है कि:
(A) यह राज्य को अत्यधिक शक्ति प्रदान करता है।
(B) यह पर्याप्त रूप से समतावादी नहीं है।
(C) यह व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकारों की पर्याप्त रक्षा नहीं करता है।
(D) यह पहचान को आकार देने में स्व की सामाजिक प्रकृति को स्वीकार करने में विफल रहता है।

293. 'दार्शनिक राजा' का विचार किसके राजनीतिक दर्शन का केंद्र है?
(A) अरस्तू
(B) मैकियावेली
(C) प्लेटो
(D) सुकरात

294. रॉबर्ट नोजिक के अनुसार राज्य की प्राथमिक भूमिका क्या है?
(A) धन का पुनर्वितरण करना और सामाजिक समानता सुनिश्चित करना।
(B) एक 'नाइट-वॉचमैन' के रूप में कार्य करना, व्यक्तियों को बल, चोरी और धोखाधड़ी से बचाना।
(C) अच्छे जीवन की एक विशिष्ट अवधारणा को बढ़ावा देना।
(D) अर्थव्यवस्था का प्रबंधन करना और कल्याणकारी सेवाएँ प्रदान करना।

295. लेनिन और माओ के क्रांतिकारी सिद्धांतों के बीच मुख्य अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है?
(A) लेनिन एक अग्रगामी दल में विश्वास करते थे, जबकि माओ ने स्वतःस्फूर्त जन विद्रोह की वकालत की।
(B) लेनिन एक भौतिकवादी थे, जबकि माओ एक आदर्शवादी थे।
(C) लेनिन ने साम्राज्यवाद का समर्थन किया, जबकि माओ ने इसका विरोध किया।
(D) लेनिन ने शहरी सर्वहारा वर्ग पर ध्यान केंद्रित किया, जबकि माओ ने किसान वर्ग पर बल दिया।

296. "मेरा स्थान और उसके कर्तव्य" नैतिकता और स्वत्व के एक ऐसे दृष्टिकोण को दर्शाता है जो किस विचारधारा के साथ अधिक संरेखित है?
(A) समुदायवाद और हेगेलवाद
(B) उदारवाद
(C) उदारतावाद
(D) उपयोगितावाद

297. बेंथम का उपयोगिता का सिद्धांत कार्यों का आकलन उनके क्या उत्पन्न करने की प्रवृत्ति के आधार पर करता है:
(A) न्याय और अधिकार
(B) दैवीय स्वीकृति
(C) सुख और दुख
(D) ऐतिहासिक प्रगति

298. अपने न्याय के सिद्धांत में, जॉन रॉल्स किसे प्राथमिकता देते हैं?
(A) शुभ पर अधिकार को।

Downloaded from www.pdf.tube

(B) अधिकार पर शुभ को।
(C) व्यक्ति पर समुदाय को।
(D) अधिकारों पर उपयोगिता को।

299. निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें:
1. ग्राम्शी - जैविक बुद्धिजीवी
2. नोजिक - न्यूनतम राज्य
3. ग्रीन - सामान्य इच्छा

उपरोक्त में से कौन सा/से युग्म सही सुमेलित है/हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2, और 3

300. एक सामाजिक और राजनीतिक समस्या के रूप में 'महिलाओं की अधीनता' का व्यवस्थित विश्लेषण किसके द्वारा एक प्रमुख कृति में किया गया था?
(A) कार्ल मार्क्स
(B) जॉन स्टुअर्ट मिल
(C) जी.डब्ल्यू.एफ. हेगेल
(D) जेरेमी बेंथम

NODIA

उत्तर (व्याख्या सहित)

1. (B) प्रजा का कल्याण और सुख
कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार राजा का सर्वोच्च धर्म प्रजा की सेवा करना है। राजा की शक्ति और अस्तित्व का मुख्य आधार प्रजा का कल्याण ही है। राजा के स्वयं के सुख में सुख नहीं है, बल्कि उसका वास्तविक सुख प्रजा की प्रसन्नता और उनकी समृद्धि में निहित होता है। एक आदर्श शासक को सदैव प्रजा के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए।

2. (A) एक शासक जिसके पास 'शुभ के स्वरूप' का सच्चा ज्ञान है और वह उसी के अनुसार शासन करता है।
प्लेटो के अनुसार दार्शनिक राजा वह है जिसने कठोर शिक्षा से परम सत्य और शुभ के विचार का ज्ञान प्राप्त किया है। ऐसा शासक व्यक्तिगत स्वार्थ से मुक्त होकर केवल विवेक के आधार पर शासन करता है। वह राज्य की भलाई के लिए कार्य करता है क्योंकि उसे वास्तविकता की गहन समझ होती है। शासन का आधार कानून नहीं, बल्कि शासक का उत्कृष्ट विवेक होता है।

3. (C) स्व का शासन और आत्म-नियंत्रण।
महात्मा गांधी के लिए स्वराज का अर्थ केवल विदेशी शासन से मुक्ति नहीं था, बल्कि यह व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर आत्म-अनुशासन का प्रतीक था। यह स्वयं पर शासन करने की क्षमता और आंतरिक स्वतंत्रता से जुड़ा विचार है। गांधी जी का मानना था कि जब व्यक्ति अपनी इंद्रियों और इच्छाओं पर नियंत्रण करना सीख जाता है, तभी वह वास्तविक अर्थों में स्वराज का अधिकारी बनता है।

4. (D) लोकतंत्र पॉलिटी का विकृत रूप है, जो सभी के हितों की पूर्ति करता है।
अरस्तू ने संविधानों को शासकों की संख्या और शासन के उद्देश्य के आधार पर वर्गीकृत किया। उनके अनुसार लोकतंत्र शासन का एक विकृत रूप है क्योंकि यह केवल निर्धन वर्ग के स्वार्थों की पूर्ति पर केंद्रित होता है, न कि संपूर्ण समाज के सामान्य हित पर। इसके विपरीत संवैधानिक तंत्र शासन का शुद्ध रूप है जो मध्यम वर्ग के माध्यम से सामान्य जनता का कल्याण सुनिश्चित करता है।

5. (C) शेर और लोमड़ी
मैकियावेली ने शासक को राजनीति में सफल होने के लिए शेर और लोमड़ी दोनों के गुणों को अपनाने की सलाह दी थी। राजा को शेर की तरह शक्तिशाली और साहसी होना चाहिए ताकि वह शत्रुओं को डरा सके। साथ ही उसे लोमड़ी की तरह चतुर होना चाहिए ताकि वह साजिशों के जाल को पहचान सके। यह सिद्धांत शक्ति और बुद्धिमानी के संतुलन पर बल देता है।

6. (B) धर्म
कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत राज्य के सात अंग अनिवार्य माने गए हैं जिनमें स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र शामिल हैं। धर्म इस विशेष सात तत्वों वाली सूची का प्रत्यक्ष हिस्सा नहीं है, हालांकि यह शासन का एक नैतिक आधार अवश्य है। सप्तांग सिद्धांत राज्य की संरचना को एक जीवित जीव की तरह देखता है जिसमें प्रत्येक अंग की विशिष्ट भूमिका होती है।

7. (A) P-3, Q-4, R-1, S-2
एम.एन. रॉय ने अपने उत्तरवर्ती जीवन में मौलिक मानवतावाद का प्रतिपादन किया था। जयप्रकाश नारायण ने सत्ता के केंद्रीकरण के विरुद्ध संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। अरविंदो घोष आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के प्रणेता थे, जो राष्ट्र को एक दैवीय शक्ति मानते थे। बी.आर. अंबेडकर ने अपनी प्रसिद्ध कृति में जाति व्यवस्था के विनाश और सामाजिक समानता पर बल दिया। ये सभी विचार भारतीय राजनीतिक चिंतन के आधार हैं।

8. (A) लेविआथन
थॉमस हॉब्स ने अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक लेविआथन में प्राकृतिक अवस्था का चित्रण अत्यंत भयावह रूप में किया है। उनके अनुसार राजनीतिक समाज के उदय से पूर्व मनुष्य निरंतर संघर्ष और भय की स्थिति में रहता था जहाँ हर व्यक्ति दूसरे का शत्रु था। शक्ति और स्वार्थ ही जीवन के मुख्य आधार थे। इसी अराजकता को समाप्त करने के लिए लोगों ने संप्रभु सत्ता की स्थापना की।

9. (C) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
जॉन लॉक को आधुनिक उदारवाद का जनक माना जाता है क्योंकि उन्होंने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सहमति आधारित शासन पर बल दिया। हालांकि लॉक ने पूर्ण और अविभाज्य संप्रभुता की नहीं, बल्कि सीमित और उत्तरदायी सरकार की वकालत की थी। उनके अनुसार सरकार एक न्यास के समान है जिसे जनता के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। यदि सरकार विफल होती है, तो जनता को विद्रोह का अधिकार है।

10. (A) अरविंदो घोष
अरविंदो घोष ने महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन से बहुत पहले ही निष्क्रिय प्रतिरोध के सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। उन्होंने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी के प्रचार को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशक्त राजनीतिक हथियार माना था। उनका मानना था कि औपनिवेशिक सत्ता को सहयोग देना बंद करके ही राष्ट्र को स्वतंत्र कराया जा सकता है। यह विचार उस समय के उग्र राष्ट्रवाद की रणनीति थी।

11. (A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
प्लेटो का न्याय सिद्धांत कार्य विशिष्टीकरण पर आधारित है। उनका मानना था कि समाज में न्याय तभी संभव है जब शासक, सैनिक और उत्पादक वर्ग अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट

Click Here to Buy book on Amazon

कार्यों का संपादन करें। जब प्रत्येक वर्ग दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप किए बिना अपनी विशेषज्ञता का पालन करता है, तब राज्य में संतुलन बना रहता है। यह कार्यात्मक विभाजन एक सुव्यवस्थित समाज की अनिवार्य शर्त है।

12. (B) ज्यां-जैक रुसो
रूसो ने अपनी सामाजिक अनुबंध की अवधारणा में सामान्य इच्छा के सिद्धांत को केंद्र में रखा। उनके अनुसार सामान्य इच्छा व्यक्तिगत स्वार्थों का योग नहीं, बल्कि पूरे समुदाय के सामूहिक कल्याण की इच्छा होती है। यह इच्छा हमेशा न्यायसंगत और राज्य के हितों के प्रति समर्पित होती है। रूसो का मानना था कि वास्तविक संप्रभुता इसी सामान्य इच्छा में निहित है और नागरिक इसी में स्वतंत्रता पाते हैं।

13. (C) राजा के कर्तव्य और दायित्व।
महाभारत के शांति पर्व में राजधर्म का विस्तृत विवरण दिया गया है, जो मुख्य रूप से राजा के नैतिक और प्रशासनिक कर्तव्यों से संबंधित है। इसके अनुसार राजा का धर्म अपनी प्रजा की रक्षा करना, न्याय व्यवस्था बनाए रखना और धर्म के अनुसार शासन करना है। राजधर्म केवल सत्ता के उपयोग का अधिकार नहीं है, बल्कि यह प्रजा के प्रति राजा की जवाबदेही का मार्ग है।

14. (C) केवल 1 और 3
डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने जाति व्यवस्था को भारतीय समाज के लिए अभिशाप माना और इसके पूर्ण उन्मूलन की वकालत की। उन्होंने संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में भारत के संविधान निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया। हालांकि वे राजनीतिक स्वतंत्रता से अधिक सामाजिक और आर्थिक समानता को महत्व देते थे। उनका मानना था कि बिना सामाजिक न्याय के राजनीतिक लोकतंत्र लंबे समय तक नहीं टिकेगा।

15. (A) अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख।
जेरेमी बेंथम के उपयोगितावाद का मूल मंत्र यह है कि किसी भी कानून की वैधता उसके द्वारा उत्पन्न सुख की मात्रा से तय होती है। उनके अनुसार समाज का मुख्य लक्ष्य अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम सुख सुनिश्चित करना होना चाहिए। यह सिद्धांत नैतिकता को परिणामों के आधार पर मापता है। बेंथम ने सुख और दुख को मानव आचरण के दो संप्रभु स्वामी माना और इसे वैज्ञानिक आधार दिया।

16. (B) राज्य किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता में केवल दूसरों को हानि से बचाने के लिए हस्तक्षेप कर सकता है।
जे.एस. मिल ने तर्क दिया कि व्यक्ति अपनी इच्छाओं और कार्यों में पूर्णतः स्वतंत्र है। राज्य को किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता में बाधा डालने का अधिकार केवल तभी है जब उसके कार्यों से समाज के किसी अन्य व्यक्ति को प्रत्यक्ष हानि पहुँचती हो। यह सिद्धांत व्यक्तिगत स्वायत्तता की रक्षा करता है और राज्य के अनावश्यक हस्तक्षेप को सीमित करता है। इसे हानि सिद्धांत के नाम से जानते हैं।

17. (B) पड़ोसी राज्य जो स्वाभाविक शत्रु है।
कौटिल्य के मंडल सिद्धांत में अंतर-राज्यीय संबंधों का विश्लेषण किया गया है। इस सिद्धांत के अनुसार राजा की सीमा से सटा हुआ पड़ोसी राज्य 'अरि' कहलाता है, जो भौगोलिक स्थिति के कारण स्वाभाविक रूप से शत्रु होता है। कौटिल्य का मानना था कि सीमावर्ती राज्यों के बीच संसाधनों को लेकर संघर्ष की संभावना सदैव बनी रहती है। इसलिए एक राजा को अपने पड़ोसी के प्रति सदैव सतर्क रहना चाहिए।

18. (A) विश्व का ऐतिहासिक विकास एक तार्किक और समझने योग्य स्वरूप का अनुसरण करता है।
हेगेल के अनुसार वास्तविकता और तर्कसंगतता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उनका मानना था कि इतिहास की प्रत्येक घटना एक उच्च उद्देश्य या परम आत्मा की प्रगति का हिस्सा है। विश्व का क्रमिक विकास कोई आकस्मिक घटना नहीं है, बल्कि यह एक द्वंद्वात्मक और तर्कसंगत प्रक्रिया के माध्यम से सत्य की ओर बढ़ता है। यह विचार इतिहास को एक व्यवस्थित बौद्धिक यात्रा के रूप में देखता है।

19. (C) मैकियावेली - द सोशल कॉन्ट्रैक्ट
मैकियावेली की प्रसिद्ध रचना 'द प्रिंस' है, जिसमें उन्होंने शासन-कला और सत्ता प्राप्ति के व्यावहारिक सिद्धांतों का वर्णन किया है। 'द सोशल कॉन्ट्रैक्ट' के लेखक ज्यां-जैक रुसो हैं, जिन्होंने सामान्य इच्छा और लोकप्रिय संप्रभुता का समर्थन किया। अन्य विकल्प सही सुमेलित हैं क्योंकि प्लेटो ने 'द रिपब्लिक', अरस्तू ने 'पॉलिटिक्स' और हॉब्स ने 'लेविआथन' नामक कालजयी कृतियों की रचना की थी। ये सभी कृतियाँ अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

20. (A) 2, 1, 3, 4
इन विचारकों का जन्म कालानुसार इस प्रकार है: निकोलो मैकियावेली का जन्म 1469 में हुआ था। थॉमस हॉब्स का जन्म 1588 में हुआ, जिन्होंने लेविआथन की रचना की। जॉन लॉक का जन्म 1632 में हुआ, जिन्हें उदारवाद का पिता कहा जाता है। अंत में ज्यां-जैक रुसो का जन्म 1712 में हुआ। यह क्रम राजनीतिक दर्शन के विकास में यथार्थवाद से लेकर सामाजिक अनुबंध के सिद्धांतों के विस्तार को दर्शाता है।

21. (C) श्रमिकों का उनके उत्पादों, स्वयं से और अन्य लोगों से अलगाव।
कार्ल मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था में श्रमिक अपने द्वारा उत्पादित वस्तुओं पर नियंत्रण खो देता है। उत्पादन की प्रक्रिया उसे एक यंत्र बना देती है, जिससे वह न केवल अपने काम से, बल्कि अपनी मानवीय प्रकृति और साथी श्रमिकों से भी अलग हो जाता है। यह अलगाव की स्थिति श्रमिकों को मानसिक रूप से रिक्त कर देती है। मार्क्स ने इसे पूंजीवाद का गहरा मानवीय संकट माना था।

22. (B) टी.एच. ग्रीन
टी.एच. ग्रीन ने सकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया, जिसके अनुसार स्वतंत्रता केवल बाधाओं की अनुपस्थिति नहीं है। उनके लिए स्वतंत्रता का अर्थ कुछ करने या आनंद लेने योग्य कार्य करने की वास्तविक क्षमता

NODIA

है। ग्रीन का मानना था कि राज्य को अशिक्षा और निर्धनता जैसी बाधाओं को दूर करना चाहिए ताकि व्यक्ति अपनी क्षमताओं का विकास कर सके। यह विचार उदारवाद को सामाजिक कल्याण से जोड़ता है।

23. (D) एकाधिकार पूंजीवाद के लिए एक अनिवार्य आर्थिक आवश्यकता।
लेनिन ने तर्क दिया कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम और उच्चतम चरण है। जब घरेलू बाजार में पूंजी का संचय बहुत अधिक हो जाता है, तो पूंजीपति नए बाजारों और कच्चे माल की तलाश में पिछड़े देशों पर नियंत्रण करते हैं। यह आर्थिक आवश्यकता राष्ट्रों के बीच संघर्ष और युद्ध का कारण बनती है। लेनिन के अनुसार साम्राज्यवाद पूंजीवादी शोषण के वैश्विक विस्तार का ही एक हिंसक रूप है।

24. (A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
एम.एन. रॉय का राजनीतिक जीवन विविध चरणों से गुजरा। वे शुरुआत में एक सक्रिय कम्युनिस्ट थे, लेकिन बाद में उन्होंने मानवतावाद की ओर रुख किया। उन्होंने मौलिक मानवतावाद के माध्यम से एक ऐसे समाज की कल्पना की जहाँ सत्ता सीधे लोगों के हाथों में हो और व्यक्ति की तर्कसंगतता सर्वोपरि हो। उनका यह दर्शन दलविहीन लोकतंत्र पर बल देता है जो दलीय राजनीति के दोषों से मुक्त है।

25. (C) यह विचार कि एक मुख्य अंतर्विरोध किसी प्रक्रिया की प्रकृति को निर्धारित करता है।
माओ जेदोंग ने अंतर्विरोध के सिद्धांत को मार्क्सवादी द्वंद्ववाद के केंद्र में रखा। उनका मानना था कि किसी भी जटिल स्थिति में कई अंतर्विरोध होते हैं, लेकिन उनमें से एक 'प्रधान अंतर्विरोध' होता है जो विकास की दिशा तय करता है। जब तक इस मुख्य समस्या का समाधान नहीं होता, अन्य गौण अंतर्विरोधों को सुलझाना कठिन होता है। यह अवधारणा माओ की रणनीतिक सोच के लिए महत्वपूर्ण आधार प्रदान करती है।

26. (A) एक शासक वर्ग का नेतृत्व जो जनता की सहमति प्राप्त करता है।
एंटोनियो ग्राम्शी ने वैचारिक प्रभुत्व की अवधारणा के माध्यम से यह समझाया कि शासक वर्ग केवल पुलिस के बल पर शासन नहीं करता। वह सांस्कृतिक संस्थानों जैसे शिक्षा और मीडिया के माध्यम से अपनी विचारधारा को समाज में फैलाता है। जब आम जनता शासक वर्ग के मूल्यों को स्वाभाविक मानकर स्वीकार कर लेती है, तब यह सहमतिपूर्ण वर्चस्व स्थापित होता है। यह राज्य की सत्ता को सुदृढ़ बनाता है।

27. (B) P-3, Q-4, R-1, S-2
जॉन रॉल्स की प्रसिद्ध कृति 'ए थ्योरी ऑफ जस्टिस' न्याय के आधुनिक सिद्धांतों का आधार है। रॉबर्ट नोजिक ने न्यूनतम राज्य और व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकारों का समर्थन किया। जे.एस. मिल की 'ऑन लिबर्टी' व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आजादी का सशक्त बचाव करती है। निकोलो मैकियावेली की 'द प्रिंस' राजनीति के यथार्थवादी पहलुओं पर प्रकाश डालती है। ये पुस्तकें राजनीति विज्ञान के इतिहास की प्रभावशाली रचनाएँ हैं।

28. (B) समाज में किसी के स्थान या प्राकृतिक क्षमताओं के ज्ञान को रोकना।
जॉन रॉल्स के अनुसार अज्ञानता का पर्दा एक ऐसी स्थिति है जहाँ न्याय के सिद्धांतों को चुनते समय व्यक्तियों को अपनी वास्तविक सामाजिक स्थिति या प्रतिभा का ज्ञान नहीं होता। इस स्थिति में व्यक्ति निष्पक्ष निर्णय लेते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि पर्दे के हटने पर वे समाज के वंचित वर्ग का हिस्सा हो सकते हैं। यह विधि न्याय के सिद्धांतों को समाज में निष्पक्षता और समानता देती है।

29. (C) स्वरुपित वितरण का सिद्धांत।
रॉबर्ट नोजिक ने स्वरुपित वितरण के सिद्धांतों की आलोचना की है क्योंकि ये वितरण के किसी पूर्व-निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। उनके न्याय के सिद्धांत में केवल तीन तत्व शामिल हैं: अधिग्रहण में न्याय, हस्तांतरण में न्याय और अन्याय का सुधार। नोजिक के अनुसार यदि किसी वस्तु को न्यायपूर्ण तरीके से प्राप्त किया गया है, तो उसका वितरण भी स्वतः न्यायपूर्ण माना जाना चाहिए।

30. (A) केवल 1 और 2
समुदायवादी विचारक उदारवाद के इस विचार का विरोध करते हैं कि व्यक्ति समाज से स्वतंत्र एक पृथक इकाई है। उनका तर्क है कि हमारी पहचान और मूल्य उस समुदाय से गहराई से जुड़े होते हैं जिसमें हम रहते हैं। यद्यपि वे समुदाय के महत्व पर बल देते हैं, लेकिन वे अनिवार्य रुप से एक न्यूनतम राज्य का समर्थन नहीं करते। इसके विपरीत, कई समुदायवादी राज्य को साझा मूल्यों को बढ़ावा देने वाला मानते हैं।

31. (A) यह अराजकता की स्थिति से बचने के लिए लोगों के बीच एक सामाजिक अनुबंध से उत्पन्न हुआ।
शांति पर्व के अनुसार प्राचीन काल में जब लोग अराजकता से त्रस्त हो गए, तो उन्होंने मिलकर आपसी समझौते किए। इस सामाजिक अनुबंध के फलस्वरूप मनु को प्रथम राजा के रूप में स्वीकार किया गया ताकि वे कानून व्यवस्था और सुरक्षा सुनिश्चित कर सकें। यह विचार पश्चिमी सामाजिक अनुबंध सिद्धांतों के समान ही राज्य की उत्पत्ति को लोगों की सुरक्षा और शांति की आवश्यकता के परिणाम के रूप में प्रस्तुत करता है।

32. (B) जय प्रकाश नारायण
जय प्रकाश नारायण ने 1970 के दशक में संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। इसका उद्देश्य समाज के सभी सात आयामों—राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, शैक्षणिक और आध्यात्मिक—में आमूलचूल परिवर्तन लाना था। वे सत्ता के अत्यधिक केंद्रीकरण और भ्रष्टाचार के विरुद्ध थे। संपूर्ण क्रांति का लक्ष्य वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना करना था जहाँ शक्ति सीधे जनता के हाथों में हो और नैतिक मूल्यों का पुनरुत्थान हो सके।

Downloaded from www.pdf.tube

33. (B) यह विचार कि एक हिंदू भारत को अपनी पितृभूमि और पुण्यभूमि दोनों मानता है।
वी.डी. सावरकर ने हिंदुत्व को एक राजनीतिक और सांस्कृतिक पहचान के रूप में परिभाषित किया। उनके अनुसार हिंदू वह है जो भारत को अपनी पितृभूमि मानता है और जिसके पवित्र तीर्थ स्थल इसी भौगोलिक सीमा के भीतर स्थित हैं। यह परिभाषा केवल धार्मिक विश्वासों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह साझा संस्कृति और राष्ट्र के प्रति निष्ठा पर आधारित है। सावरकर ने हिंदू राष्ट्रवाद की एक सैद्धांतिक रूपरेखा प्रस्तुत की।

34. (A) पॉलिटी, क्योंकि यह अल्पतंत्र और लोकतंत्र को संतुलित करने वाला एक मिश्रित संविधान है।
अरस्तू के अनुसार स्वर्णिम मध्य का सिद्धांत अतिवादी स्थितियों से बचने और संतुलन बनाए रखने पर जोर देता है। वे संवैधानिक तंत्र को सर्वोत्तम व्यवहार्य शासन मानते हैं क्योंकि यह अमीरों के अल्पतंत्र और गरीबों के लोकतंत्र के बीच संतुलन स्थापित करता है। इसमें मध्यम वर्ग की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, जो समाज में स्थिरता लाता है और वर्ग संघर्ष को रोकता है। यह सबसे टिकाऊ संवैधानिक व्यवस्था मानी जाती है।

35. (C) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
रूसो ने अपनी रचनाओं में स्पष्ट किया कि निजी संपत्ति के उदय के साथ ही समाज में असमानता और संघर्ष की शुरुआत हुई। हालांकि उन्होंने यह भी तर्क दिया कि आधुनिक मनुष्य के लिए प्रकृति की उस आदिम अवस्था में पूरी तरह लौटना संभव नहीं है। इसके बजाय वे सामाजिक अनुबंध के माध्यम से एक ऐसे राजनीतिक समाज के निर्माण की वकालत करते हैं जहाँ नागरिक सामान्य इच्छा के अधीन रहकर स्वतंत्रता प्राप्त कर सकें।

36. (D) क्योंकि यह सीधे तौर पर किसी विशिष्ट व्यक्ति के विरुद्ध हिंसा के कार्य को उकसाता है।
जे.एस. मिल के अनुसार विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लगभग पूर्ण होनी चाहिए। केवल तभी किसी अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है जब वह सीधे तौर पर किसी अन्य व्यक्ति को शारीरिक हानि पहुँचाने के लिए उकसाती हो। मिल का मानना था कि बहुमत द्वारा किसी विचार को दबाना सत्य की खोज में बाधक है। जब विचारों में टकराव होता है, तभी समाज सत्य के अधिक निकट पहुँच पाता है।

37. (A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
कार्ल मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी राज्य एक तटस्थ संस्था नहीं है, बल्कि यह बुर्जुआ वर्ग की कार्यकारिणी समिति के समान कार्य करता है। राज्य की मशीनरी का उपयोग उत्पादन के साधनों के स्वामियों के हितों की रक्षा करने और सर्वहारा वर्ग के विद्रोह को दबाने के लिए किया जाता है। कानून और पुलिस सभी पूंजीपति वर्ग के वर्चस्व को बनाए रखने में सहायक होते हैं। मार्क्स के अनुसार इसका उन्मूलन अनिवार्य है।

38. (B) रॉबर्ट नोजिक
रॉबर्ट नोजिक ने एक अत्यंत सीमित राज्य का समर्थन किया है, जिसे 'नाइट-वॉचमैन स्टेट' कहा जाता है। उनके अनुसार राज्य का कार्य केवल बल प्रयोग, चोरी और धोखाधड़ी से सुरक्षा प्रदान करने तक ही सीमित होना चाहिए। इससे अधिक कोई भी हस्तक्षेप व्यक्तिगत अधिकारों और संपत्ति का उल्लंघन है। नोजिक कल्याणकारी राज्य के पुनर्वितरणकारी कार्यों को अनैतिक मानते हैं क्योंकि वे व्यक्तियों की मेहनत की कमाई पर अनुचित कर लगाते हैं।

39. (D) सभी का कल्याण।
सर्वोदय गांधीवादी दर्शन का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, जिसका शाब्दिक अर्थ 'सभी का उदय' या 'सबका कल्याण' है। इसका मुख्य विचार यह है कि समाज की प्रगति तभी सार्थक है जब वह अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति के उत्थान को सुनिश्चित करे। सर्वोदय शोषण मुक्त, अहिंसक और सहयोग पर आधारित समाज की कल्पना करता है जहाँ अमीर-गरीब का भेद समाप्त हो और प्रत्येक व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन प्राप्त हो।

40. (A) चर्चा की पूर्ण स्वतंत्रता, लेकिन कार्रवाई की पूर्ण एकता।
लेनिन के लोकतांत्रिक केंद्रीयवाद का सिद्धांत पार्टी के भीतर निर्णय लेने की प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत नीति निर्धारण के चरण में पार्टी के सभी सदस्यों को स्वतंत्र रूप से चर्चा और असहमति व्यक्त करने का अधिकार होता है। परंतु एक बार जब बहुमत से कोई निर्णय ले लिया जाता है, तो सभी सदस्यों के लिए उसका कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होता है। यह सिद्धांत पार्टी में अनुशासन और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करता है।

41. (C) अज्ञानता से ज्ञान के प्रकाश तक की यात्रा को दर्शाने वाली एक कहानी।
प्लेटो का गुफा का रूपक शिक्षा और ज्ञान की प्रकृति को समझाने के लिए एक प्रसिद्ध उदाहरण है। इसमें गुफा में बंधे कैदी केवल परछाइयों को वास्तविकता मानते हैं, जो अज्ञानता का प्रतीक है। जब एक कैदी बाहर निकलकर सूर्य के प्रकाश को देखता है, तो उसे वास्तविक सत्य का बोध होता है। यह कहानी दर्शाती है कि दार्शनिक का कार्य समाज को भ्रम की दुनिया से बाहर निकालना है।

NODIA

42. (A) एक मजबूत और जटिल नागरिक समाज वाले समाज।
ग्राम्शी के अनुसार पश्चिमी लोकतांत्रिक समाजों में शासक वर्ग ने नागरिक समाज के माध्यम से अपना गहरा वैचारिक प्रभाव स्थापित किया है। ऐसे समाजों में केवल राज्य की शक्ति पर प्रहार पर्याप्त नहीं है। इसके बजाय क्रांतिकारियों को एक दीर्घकालिक वैचारिक संघर्ष छेड़ना पड़ता है जिसे 'स्थिति का युद्ध' कहा जाता है। इसका लक्ष्य समाज की संस्थाओं में घुसपैठ करना और धीरे-धीरे जनमानस में शासक वर्ग के वर्चस्व को दुर्बल करना है।

43. (D) सुख
जॉन लॉक ने तर्क दिया कि मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में ही कुछ अपरिहार्य अधिकारों के साथ जन्म लेता है। इनमें जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार प्रमुख हैं। सरकार की स्थापना का मुख्य उद्देश्य इन तीन प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करना ही है। यद्यपि 'सुख की खोज' का विचार बाद में प्रसिद्ध हुआ,

लेकिन लॉक के मूल राजनीतिक दर्शन में सुख को कानूनी रूप से संरक्षित प्राकृतिक अधिकार की श्रेणी में नहीं रखा गया था।

44. (A) 4, 3, 1, 2
इन कृतियों का प्रकाशन कालानुक्रमिक रूप से इस प्रकार है: कार्ल मार्क्स का 'कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो' 1848 में प्रकाशित हुआ। जे.एस. मिल की 'ऑन लिबर्टी' 1859 में आई, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन करती है। जॉन रॉल्स की 'ए थ्योरी ऑफ जस्टिस' 1971 में प्रकाशित हुई, जिसने न्याय के विमर्श को बदल दिया। अंत में रॉबर्ट नोज़िक की 'एनार्की, स्टेट, एंड यूटोपिया' 1974 में आई, जो रॉल्स के सिद्धांतों की प्रतिक्रिया थी।

45. (C) महाभारत
शांति पर्व हिंदू महाकाव्य महाभारत के अठारह पर्वों में से बारहवां पर्व है। कुरुक्षेत्र के युद्ध के समापन के बाद, पितामह भीष्म युधिष्ठिर को राजधर्म, शासन व्यवस्था और नैतिकता का उपदेश देते हैं। इसमें प्राचीन भारतीय राजनीतिक दर्शन, राजा के कर्तव्यों और संकट काल में अपनाई जाने वाली नीतियों का विस्तृत संग्रह है। यह ग्रंथ भारतीय राजनीति विज्ञान और धर्मशास्त्र के महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक माना जाता है।

46. (D) द सोशल कॉन्ट्रैक्ट
रूसो की पुस्तक 'द सोशल कॉन्ट्रैक्ट' की यह प्रसिद्ध शुरुआती पंक्ति मनुष्य की प्राकृतिक स्वतंत्रता और सामाजिक बंधनों के बीच के विरोधाभास को रेखांकित करती है। उनका मानना था कि समाज की संस्थाओं ने मनुष्य की सहज स्वतंत्रता को छीन लिया है। इस समस्या का समाधान वे एक ऐसे सामाजिक अनुबंध में देखते हैं जहाँ व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता को सामान्य इच्छा को समर्पित कर देता है। इस प्रकार वह वास्तविक अधिकारों को प्राप्त करता है।

47. (A) सामाजिक लोकतंत्र
डॉ. बी.आर. अंबेडकर के लिए केवल राजनीतिक लोकतंत्र पर्याप्त नहीं था। उन्होंने तर्क दिया कि जब तक समाज में 'एक व्यक्ति, एक मूल्य' का सिद्धांत लागू नहीं होता, तब तक लोकतंत्र अधूरा है। इसका अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक और आर्थिक जीवन में समान सम्मान मिलना चाहिए। जाति व्यवस्था के कारण भारत में इस समानता का अभाव था, इसलिए उन्होंने सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना को अपना मुख्य लक्ष्य बनाया।

48. (B) P-2, Q-1, R-4, S-3
हेगेल ने राज्य को सर्वोच्च नैतिक संस्था मानते हुए उसे पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण कहा। टी.एच. ग्रीन सकारात्मक स्वतंत्रता के प्रमुख समर्थक थे, जो इसे आत्म-साक्षात्कार की क्षमता मानते थे। एंटोनियो ग्राम्शी ने वैचारिक वर्चस्व की अवधारणा दी, जो प्रभुत्व की व्याख्या करती है। एम.एन. रॉय ने अपने अंतिम वर्षों में मौलिक मानवतावाद का प्रतिपादन किया, जो व्यक्ति की तर्कसंगत स्वतंत्रता पर केंद्रित है। ये सभी विचारक आधुनिक सिद्धांतों के स्तंभ हैं।

49. (B) आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंडनीति
कौटिल्य के अनुसार एक कुशल राजा को चार प्रमुख विद्याओं का ज्ञान होना अनिवार्य है। आन्वीक्षिकी तर्कशास्त्र और दर्शन का विज्ञान है, त्रयी वेदों का धार्मिक ज्ञान है, वार्ता अर्थशास्त्र और संसाधनों के प्रबंधन से संबंधित है, और दंडनीति शासन कला तथा कानून व्यवस्था का विज्ञान है। इन विद्याओं में निपुणता राजा को संतुलित निर्णय लेने और प्रजा का कल्याण करने में सक्षम बनाती है। यह शिक्षा प्रणाली आदर्श शासक का आधार है।

50. (A) केवल 3
थॉमस हॉब्स के सामाजिक अनुबंध में लोग आपस में समझौता करके अपनी सभी शक्तियां एक संप्रभु को सौंप देते हैं। संप्रभु इस अनुबंध का हिस्सा नहीं होता, इसलिए वह इसकी शर्तों से बंधा हुआ नहीं है। लोग आत्म-संरक्षण के अधिकार को पूरी तरह नहीं छोड़ते, क्योंकि अनुबंध का मूल उद्देश्य ही जीवन की रक्षा करना है। चूंकि संप्रभु अनुबंध का पक्षकार नहीं है, इसलिए प्रजा के पास उसके विरुद्ध विद्रोह का अधिकार नहीं होता।

51. (C) उच्च और निम्न सुखों के बीच एक गुणात्मक अंतर प्रस्तुत किया।
जेरेमी बेंथम ने सुख को केवल मात्रात्मक रूप में देखा था। जे.एस. मिल ने इसमें संशोधन करते हुए कहा कि कुछ सुख अपनी प्रकृति में अन्यों से श्रेष्ठ होते हैं। उन्होंने बौद्धिक और नैतिक सुखों को शारीरिक सुखों से उच्च माना। मिल का प्रसिद्ध कथन है कि "एक असंतुष्ट सुकरात होना एक संतुष्ट मूर्ख होने से बेहतर है।" यह गुणात्मक अंतर उपयोगितावाद को एक उच्च नैतिक धरातल प्रदान करने का प्रयास करता है।

52. (D) ग्रामीण क्षेत्रों पर आधारित एक दीर्घकालिक जनयुद्ध छेड़ना।
चीन जैसी अर्ध-सामंती स्थितियों में, माओ जेदोंग ने 'दीर्घकालिक जनयुद्ध' की रणनीति अपनाई। उनका मानना था कि क्रांतिकारी शक्ति का मुख्य स्रोत किसान वर्ग है। इस रणनीति के तहत क्रांतिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों में मजबूत आधार बनाना चाहिए और फिर धीरे-धीरे शहरों को चारों ओर से घेरकर उन पर कब्जा करना चाहिए। यह दृष्टिकोण पारंपरिक मॉडल से अलग था, जो शहरी सर्वहारा क्रांति पर अधिक बल देता था।

53. (C) यह एक असामाजिक स्व की पूर्वकल्पना करती है, जो अपने समुदाय से अलग है।
समुदायवादी विचारकों का तर्क है कि रॉल्स की 'मूल स्थिति' में व्यक्ति को उसके सामाजिक संदर्भों से पूरी तरह अलग मान लिया गया है। वे इसे 'असंलग्न स्व' की संज्ञा देते हैं। उनके अनुसार मनुष्य की पहचान उसके परिवार और समुदाय से निर्मित होती है। न्याय के सिद्धांतों को इन सामाजिक संबंधों से काटकर नहीं समझा जा सकता। समुदायवादियों का मानना है कि रॉल्स का व्यक्तिवाद वास्तविकता से परे है और साझा मूल्यों की उपेक्षा करता है।

Click Here to Buy book on Amazon

54. (B) एम.के. गांधी
महात्मा गांधी ने न्यासिता का सिद्धांत आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए दिया था। इसके अनुसार धनी व्यक्तियों को अपनी अतिरिक्त संपत्ति का स्वामी नहीं, बल्कि समाज के लिए एक न्यासी समझना चाहिए। उन्हें अपनी आवश्यकता से अधिक धन का उपयोग जनहित और गरीबों के कल्याण के लिए करना चाहिए। गांधी जी हिंसा के माध्यम से संपत्ति छीनने के बजाय हृदय परिवर्तन के माध्यम से सामाजिक न्याय प्राप्त करना चाहते थे।

55. (A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
अरस्तू ने दासता को एक प्राकृतिक और आवश्यक संस्था माना। उनका तर्क था कि कुछ व्यक्ति जन्म से ही मानसिक रूप से कमजोर होते हैं और उनमें स्व-शासन की क्षमता नहीं होती, इसलिए उन्हें दूसरों के अधीन रहना चाहिए। दासता से स्वामी को फुर्सत मिलती है ताकि वह बौद्धिक कार्यों में भाग ले सके। यह विचार आधुनिक मानवाधिकारों के सिद्धांतों के पूर्णतः विपरीत और विवादास्पद माना जाता है।

56. (A) रॉबर्ट नोजिक
रॉबर्ट नोजिक एक प्रखर उदारतावादी विचारक हैं जो व्यक्तिगत अधिकारों और न्यूनतम राज्य के प्रबल समर्थक हैं। वे समुदायवादी विचारधारा से संबद्ध नहीं हैं। इसके विपरीत माइकल सैंडेल और चार्ल्स टेलर प्रमुख समुदायवादी विचारक माने जाते हैं जो उदारवादी व्यक्तिवाद की आलोचना करते हैं। समुदायवादी इस बात पर बल देते हैं कि व्यक्ति की पहचान और नैतिकता उसके समुदाय के साझा मूल्यों और संस्कृति से गहराई से प्रभावित होती है।

57. (C) असमानताएं समाज के सबसे कम सुविधा प्राप्त सदस्यों के लिए हितकारी होनी चाहिए।
जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत का 'भेद का सिद्धांत' यह स्वीकार करता है कि समाज में पूर्ण आर्थिक समानता संभव नहीं है। परंतु, यह सिद्धांत यह शर्त लगाता है कि सामाजिक और आर्थिक असमानताएं केवल तभी उचित मानी जा सकती हैं जब वे समाज के सबसे वंचित वर्ग के अधिकतम लाभ के लिए कार्य करें। यह अवधारणा एक न्यायपूर्ण समाज में संसाधनों के पुनर्वितरण और कल्याणकारी राज्य की नीतियों को नैतिक आधार प्रदान करती है।

58. (A) विवेक, साहस और तृष्णा
प्लेटो ने मानव आत्मा को तीन तत्वों में विभाजित किया: विवेक, साहस और तृष्णा। उनके अनुसार एक संतुलित व्यक्ति में विवेक का शासन होना चाहिए। इसी आधार पर उन्होंने राज्य के तीन वर्गों की कल्पना की: दार्शनिक शासक, सैनिक और उत्पादक। जब आत्मा के ये तीनों भाग अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करते हैं और विवेक के अधीन रहते हैं, तभी व्यक्ति और राज्य दोनों में न्याय की स्थापना संभव हो पाती है।

59. (D) शासन या लोक प्रशासन का विज्ञान।
कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दंडनीति का अर्थ केवल दंड देना नहीं है, बल्कि यह शासन चलाने की संपूर्ण विद्या है। इसमें कानून का प्रवर्तन, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना और राज्य की सुरक्षा के सिद्धांत शामिल हैं। कौटिल्य का मानना था कि बिना दंड की शक्ति के समाज में अराजकता फैल जाएगी। दंडनीति एक ऐसा साधन है जो धर्म, अर्थ और काम की रक्षा करता है और राजा को शासन के दिशा-निर्देश प्रदान करता है।

60. (B) कार्ल मार्क्स
हेगेल ने तर्क दिया था कि विचार ही भौतिक वास्तविकता को आकार देते हैं। कार्ल मार्क्स ने इस विचार को पूरी तरह उलट दिया और 'ऐतिहासिक भौतिकवाद' का सिद्धांत दिया। मार्क्स के अनुसार भौतिक और आर्थिक स्थितियां ही विचारों और चेतना का निर्माण करती हैं। उन्होंने कहा कि हेगेल का द्वंद्ववाद सिर के बल खड़ा था, जिसे उन्होंने उत्पादन के साधनों और भौतिक आधार पर टिके होने के कारण पैरों के बल खड़ा कर दिया।

61. (C) व्यक्तिगत मानव
एम.एन. रॉय का मौलिक मानवतावाद व्यक्ति की संप्रभुता और स्वतंत्रता पर आधारित है। वे किसी भी सामूहिक पहचान जैसे राष्ट्र या धर्म को व्यक्ति से ऊपर नहीं मानते। उनके अनुसार मनुष्य स्वभाव से तर्कसंगत है और उसे अपनी नियति का स्वयं निर्माता होना चाहिए। यह दर्शन सत्ता के विकेंद्रीकरण और दलविहीन लोकतंत्र की वकालत करता है जहाँ प्रत्येक व्यक्ति अपनी गरिमा के साथ समाज के निर्माण में सक्रिय रूप से भाग ले सके।

62. (D) उनका मानना था कि सरकार का गणतंत्रवादी रूप स्वाभाविक रूप से अस्थिर और अवांछनीय है।
मैकियावेली के बारे में यह धारणा गलत है कि वे गणतंत्रवाद के विरोधी थे। वास्तव में अपनी पुस्तक 'डिसकोर्सेस ऑन लिवी' में उन्होंने गणतंत्र को सरकार का सबसे उत्कृष्ट और स्थिर रूप माना है। यद्यपि 'द प्रिंस' में उन्होंने इटली की तत्कालीन अराजक स्थिति में एक शक्तिशाली शासक की आवश्यकता पर बल दिया, लेकिन उनके दीर्घकालिक आदर्शों में स्वतंत्रता और कानून के शासन पर आधारित गणतंत्रवादी व्यवस्था ही सर्वोपरि थी।

63. (B) केवल 2
रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा हमेशा सामान्य हित और सार्वजनिक भलाई के लक्ष्य से प्रेरित होती है। यह केवल व्यक्तिगत स्वार्थों का कुल योग नहीं है, जिसे रूसो 'सभी की इच्छा' कहते हैं। सामान्य इच्छा कभी गलत नहीं हो सकती क्योंकि वह पूरे समाज की सामूहिक नैतिकता का प्रतिनिधित्व करती है। रूसो ने यह भी तर्क दिया कि इस इच्छा का प्रतिनिधित्व निर्वाचित अधिकारियों द्वारा नहीं किया जा सकता; इसे नागरिकों द्वारा सीधे व्यक्त किया जाना चाहिए।

64. (B) नैतिक विकास और आत्म-साक्षात्कार के मार्ग की बाधाओं को दूर करना।
टी.एच. ग्रीन के अनुसार राज्य का उद्देश्य केवल बल प्रयोग या कानून व्यवस्था बनाए रखना नहीं है। राज्य एक ऐसी संस्था है जिसका कार्य व्यक्ति के नैतिक जीवन में आने वाली बाधाओं को हटाना है। वे इन बाधाओं को 'बाधाओं की बाधा' कहते हैं।

Downloaded from www.pdf.tube

निर्धनता और अज्ञानता जैसी सामाजिक बुराइयों को दूर करके राज्य व्यक्ति को स्वतंत्र बनाता है ताकि वह अपने उच्चतम स्वरुप को प्राप्त कर सके। यह विचार सकारात्मक उदारवाद का आधार है।

65. (B) समाज का भौतिक या आर्थिक आधार उसके राजनीतिक और वैचारिक अधिरचना को निर्धारित करता है।
ऐतिहासिक भौतिकवाद मार्क्सवादी दर्शन का केंद्र है। इसके अनुसार किसी भी समाज की संरचना का मूल आधार उसकी उत्पादन पद्धति और आर्थिक संबंध होते हैं। कानून, धर्म और संस्कृति इस आधार पर टिकी हुई 'अधिरचना' हैं। जब उत्पादन की शक्तियों में परिवर्तन होता है, तो समाज के आर्थिक आधार में भी बदलाव आता है, जिससे संपूर्ण ढांचा बदल जाता है। मार्क्स के अनुसार इतिहास की प्रगति इसी भौतिक विकास का परिणाम है।

66. (A) अन्याय का विरोध करने में सत्य और अहिंसा का पालन करता है।
गांधी जी के अनुसार सत्याग्रही वह व्यक्ति है जो सत्य के प्रति दृढ़ रहता है और किसी भी परिस्थिति में अहिंसा का मार्ग नहीं छोड़ता। वह शत्रु के प्रति घृणा नहीं रखता, बल्कि अपने आत्म-कष्ट और प्रेम के माध्यम से विरोधी का हृदय परिवर्तन करने का प्रयास करता है। सत्याग्रह का अर्थ कायरतापूर्ण समर्पण नहीं, बल्कि अन्याय के विरुद्ध एक सक्रिय प्रतिरोध है। एक सच्चा सत्याग्रही सत्य की रक्षा के लिए प्राण देने को तत्पर रहता है।

67. (A) 4, 1, 3, 2
ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार, इन ग्रंथों का क्रम इस प्रकार है: महाभारत का शांति पर्व प्राचीनतम माना जाता है। इसके बाद चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में प्लेटो का 'रिपब्लिक' आया। अरस्तू की 'पॉलिटिक्स' उसके कुछ समय बाद लिखी गई। कौटिल्य का 'अर्थशास्त्र' भी मौर्य काल के दौरान रचित माना जाता है। यह क्रम प्राचीन विश्व में राजनीतिक चिंतन के समानांतर विकास को दर्शाता है। ये सभी ग्रंथ शासन कला के महत्वपूर्ण आधार हैं।

68. (D) आध्यात्मिक विकास और मानव जीवन का दैवीकरण।
अरविंदो घोष की राजनीतिक यात्रा उग्र क्रांतिकारी राष्ट्रवाद से शुरु हुई थी। अलीपुर षडयंत्र मामले के बाद उनके विचारों में गहरा आध्यात्मिक परिवर्तन आया। वे पांडिचेरी चले गए और 'पूर्ण योग' के माध्यम से मानव चेतना के विकास पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने तर्क दिया कि केवल राजनीतिक स्वतंत्रता पर्याप्त नहीं है, बल्कि मनुष्य को अपनी आंतरिक सत्ता को दिव्य बनाना होगा ताकि एक अतिमानवीय समाज का निर्माण हो सके। यह उनका दर्शन था।

69. (C) राजा सामान्य हित के लिए शासन करता है, जबकि निरंकुश शासक अपने लाभ के लिए शासन करता है।
अरस्तू के वर्गीकरण में शासन के उद्देश्य को प्राथमिकता दी गई है। उनके अनुसार राजतंत्र एक व्यक्ति का शुद्ध शासन है क्योंकि राजा पूरे समुदाय के कल्याण को ध्यान में रखकर निर्णय लेता है। इसके विपरीत, जब वही शासक केवल अपने निजी सुख और स्वार्थ के लिए शासन करने लगता है, तो वह शासन का विकृत रूप यानी 'निरंकुश शासन' बन जाता है। यहाँ भेद शासक की संख्या में नहीं, बल्कि उसके नैतिक उद्देश्य में है।

70. (A) P-4, Q-1, R-2, S-3
जे.एस. मिल ने 'हानि सिद्धांत' के माध्यम से व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सीमाएं निर्धारित कीं। जॉन रॉल्स ने 'अज्ञानता का पर्दा' नामक अवधारणा दी ताकि न्याय के सिद्धांतों का निष्पक्ष चुनाव हो सके। कार्ल मार्क्स ने पूंजीवाद के बाद 'सर्वहारा वर्ग की तानाशाही' को एक संक्रमणकालीन चरण माना। निकोलो मैकियावेली ने शासक के लिए 'वीर कौशल' और 'भाग्य' के महत्व को प्रतिपादित किया। ये सभी अवधारणाएं राजनीतिक दर्शन के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं।

71. (D) सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, वैचारिक और आध्यात्मिक
जय प्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति का विचार एक व्यापक परिवर्तन का आह्वान था। उनका मानना था कि केवल सरकार बदलने से वास्तविक लोकतंत्र नहीं आ सकता। इसके लिए व्यक्ति के जीवन के सभी सात आयामों में क्रांतिकारी सुधार आवश्यक हैं। इसमें भ्रष्टाचार का उन्मूलन, सत्ता का विकेंद्रीकरण और नैतिक मूल्यों की पुनर्स्थापना शामिल थी। यह आंदोलन जनता की सामूहिक शक्ति के माध्यम से एक नया समाज बनाने का प्रयास था।

72. (A) ज्ञान और न्याय पर ध्यान केंद्रित करते हुए राज्य पर शासन करना।
प्लेटो के आदर्श राज्य में 'संरक्षक' वर्ग में शासक और सैनिक दोनों शामिल होते हैं, लेकिन शासन का मुख्य कार्य दार्शनिक राजाओं का होता है। वे अपने ज्ञान के बल पर राज्य की नीतियों का निर्धारण करते हैं। संरक्षक वर्ग के लिए प्लेटो ने संपत्ति और परिवार के साम्यवाद की व्यवस्था की है ताकि वे निजी हितों से ऊपर उठकर निष्पक्ष रूप से न्याय कर सकें। उनकी प्राथमिकता पूरे राज्य की एकता और सद्भाव बनाए रखना है।

73. (C) बी.आर. अंबेडकर
'जाति का विनाश' डॉ. बी.आर. अंबेडकर द्वारा 1936 में लिखा गया एक अत्यंत प्रभावशाली लेख है। इस कृति में अंबेडकर ने तर्क दिया कि हिंदू समाज में जाति व्यवस्था केवल श्रम का विभाजन नहीं है, बल्कि यह श्रमिकों का विभाजन है। उन्होंने जाति को जड़ से खत्म करने के लिए उन धार्मिक आधारों को नष्ट करने की मांग की जो इस व्यवस्था को पवित्रता प्रदान करते हैं। यह सामाजिक सुधार की दिशा में एक क्रांतिकारी दस्तावेज है।

74. (A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
जॉन लॉक का सामाजिक अनुबंध सिद्धांत संवैधानिक और सीमित सरकार का प्रबल समर्थन करता है। उनके अनुसार राज्य का निर्माण लोगों के प्राकृतिक अधिकारों—जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति—की रक्षा के लिए हुआ है। राज्य एक न्यासी की भूमिका निभाता है और उसकी शक्तियां जनता की सहमति पर टिकी होती हैं। यदि शासक इन अधिकारों का उल्लंघन करता

NODIA

है, तो जनता के पास उसे हटाने और एक नई सरकार चुनने का नैतिक अधिकार होता है।

75. (D) किसी कार्य के परिणामस्वरूप होने वाले सुख या दुख की मात्रा की गणना करना।
जेरेमी बेंथम ने उपयोगिता को मापने के लिए एक सुखवादी गणना की विधि विकसित की थी। इसके मापदंडों में तीव्रता, अवधि, निश्चितता और विस्तार शामिल थे। इस पद्धति के माध्यम से वे यह निर्धारित करना चाहते थे कि कौन सा कार्य समाज में सुख की अधिकतम मात्रा और दुख की न्यूनतम मात्रा उत्पन्न करेगा। यह बेंथम के उपयोगितावादी दर्शन को एक वैज्ञानिक और मात्रात्मक आधार प्रदान करने का प्रयास था।

76. (B) आदर्शवादी और रुढ़िवादी
हेगेल का राजनीतिक दर्शन पूर्णतः आदर्शवाद पर आधारित है, जहाँ वे 'विचार' को वास्तविकता का मूल मानते हैं। वे राज्य को सर्वोच्च नैतिक सत्ता और पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिबिंब मानते हैं, जो व्यक्ति के अधिकारों से ऊपर है। उनके विचार काफी हद तक रुढ़िवादी भी हैं क्योंकि वे मौजूदा संस्थाओं और कानून के शासन का समर्थन करते हैं। हेगेल का मानना था कि राज्य में ही व्यक्ति की वास्तविक स्वतंत्रता अपनी पूर्णता प्राप्त करती है।

77. (C) जॉन लॉक
जॉन लॉक का यह कथन कानून के शासन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच के अनिवार्य संबंध को दर्शाता है। लॉक के अनुसार कानून का उद्देश्य स्वतंत्रता को समाप्त करना या प्रतिबंधित करना नहीं, बल्कि उसे संरक्षित करना है। बिना किसी नियम या कानून के समाज में केवल अराजकता और शक्ति का वर्चस्व होगा, जहाँ कोई भी वास्तव में स्वतंत्र नहीं रह पाएगा। कानून ही वह ढांचा प्रदान करता है जिसके भीतर नागरिक सुरक्षित रूप से अपने अधिकारों का आनंद ले सकते हैं।

78. (D) धर्म
कौटिल्य ने विदेश नीति के संचालन के लिए छह-चरणीय नीति का प्रतिपादन किया है। इसमें संधि, विग्रह (युद्ध), आसन (तटस्थता), यान (आक्रमण), संश्रय (शरण लेना) और द्वैधीभाव (दोहरी नीति) शामिल हैं। 'धर्म' इस कूटनीतिक सूची का हिस्सा नहीं है क्योंकि कौटिल्य की विदेश नीति मुख्य रूप से यथार्थवाद और राज्य के हित को सर्वोपरि रखने पर आधारित है। राजा को अपनी स्थिति के अनुसार इनमें से सही रणनीति का चयन करना चाहिए।

79. (A) ग्राम्शी ने राज्य को बल प्रयोग और सहमति के माध्यम से बनाए रखने वाले शासन के रूप में देखा।
पारंपरिक मार्क्सवाद राज्य को केवल दमनकारी यंत्र मानता था, लेकिन ग्राम्शी ने इसे अधिक सूक्ष्मता से समझाया। उनके अनुसार राज्य की शक्ति दो स्तंभों पर टिकी है: 'राजनीतिक समाज' जो बल का प्रयोग करता है, और 'नागरिक समाज' जो शिक्षा और संस्कृति के माध्यम से लोगों की सहमति प्राप्त करता है। इसे 'अभिन्न राज्य' कहा गया। उनके अनुसार शासक वर्ग का वर्चस्व केवल भय पर नहीं, बल्कि वैचारिक प्रभुत्व पर आधारित होता है।

80. (A) केवल 2
जे.एस. मिल लोकतंत्र के समर्थक थे लेकिन वे "बहुमत की निरंकुशता" से चिंतित थे। उन्होंने तर्क दिया कि सभी मतों का मूल्य समान नहीं होना चाहिए और शिक्षित व्यक्तियों को एक से अधिक मत देने का अधिकार मिलना चाहिए। वे गुप्त मतदान के विरुद्ध थे क्योंकि उनका मानना था कि मतदान एक सार्वजनिक कर्तव्य है जिसे उत्तरदायित्व के साथ किया जाना चाहिए। मिल केवल उन लोगों को मताधिकार देना चाहते थे जो शिक्षित थे और कर देते थे।

81. (B) जॉन रॉल्स
जॉन रॉल्स एक प्रमुख उदारवादी विचारक हैं जिन्होंने अपने कार्यों में न्याय और व्यक्तिगत अधिकारों को केंद्र में रखा है। समुदायवादी विचारकों ने रॉल्स के व्यक्तिवादी दृष्टिकोण की तीखी आलोचना की है। समुदायवादियों का मानना है कि रॉल्स व्यक्ति को उसके सामाजिक संदर्भों से काटकर एक कृत्रिम 'असंलग्न स्व' के रूप में देखते हैं। इसलिए रॉल्स समुदायवादी विचारधारा से नहीं, बल्कि उदारवादी परंपरा के सशक्त प्रस्तावक के रूप में जाने जाते हैं।

82. (A) हिंदू राष्ट्र की पहचान को परिभाषित करने वाली एक राजनीतिक और सांस्कृतिक अवधारणा।
वी.डी. सावरकर के लिए हिंदुत्व शब्द केवल धर्म का पर्याय नहीं है। यह एक व्यापक भौगोलिक और सांस्कृतिक पहचान है। इसमें वे सभी लोग शामिल हैं जो भारत को अपनी पितृभूमि और पुण्यभूमि मानते हैं। हिंदुत्व का उद्देश्य एक साझा इतिहास और राष्ट्रीय भावना के आधार पर हिंदुओं को एक राजनीतिक शक्ति के रूप में संगठित करना था। सावरकर ने इसे एक ऐसे राष्ट्र के रूप में देखा जिसकी जड़ें भारत की भूमि में हैं।

83. (C) पॉलिटी, मध्यम वर्ग द्वारा चलाई जाने वाली एक संवैधानिक सरकार।
अरस्तू ने संवैधानिक तंत्र को सबसे व्यावहारिक शासन व्यवस्था माना है। उनके अनुसार यह अल्पतंत्र और लोकतंत्र का एक मध्यम मार्ग है। इसमें सत्ता मध्यम वर्ग के हाथों में होती है, जो न तो अमीरों की तरह अहंकारी होते हैं और न ही गरीबों की तरह ईर्ष्यालु। मध्यम वर्ग की प्रधानता समाज में स्थिरता सुनिश्चित करती है और अतिवादी आंदोलनों को रोकती है, जिससे शासन व्यवस्था दीर्घजीवी बनी रहती है। यह संतुलन का मार्ग है।

84. (D) ज्यां-जैक रूसो
रूसो का यह वाक्यांश 'स्वतंत्र होने के लिए बाध्य' उनकी सामान्य इच्छा की अवधारणा से जुड़ा है। उनके अनुसार जब कोई व्यक्ति कानून का उल्लंघन करता है, तो वह वास्तव में अपनी ही वास्तविक इच्छा के विरुद्ध कार्य कर रहा होता है। राज्य उसे कानून मानने के लिए मजबूर करके उसे पुनः उसकी अपनी स्वतंत्रता और सामूहिक नैतिकता की ओर ले जाता है। रूसो का मानना था कि सामान्य इच्छा के पालन में ही सच्ची स्वतंत्रता निहित है।

Click Here to Buy book on Amazon

85. (C) प्रकृति की एक ऐसी अवस्था जहाँ बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को खा जाती हैं, जो अराजकता का प्रतीक है।
मात्स्यन्याय प्राचीन भारतीय राजनीतिक दर्शन की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो अराजकता की स्थिति का वर्णन करती है। शांति पर्व में बताया गया है कि बिना राजा और दंड की शक्ति के समाज में केवल बलवानों का बोलबाला होता है और कमजोरों का शोषण होता है। इस भयावह स्थिति को समाप्त करने और शांति तथा व्यवस्था स्थापित करने के लिए ही राज्य और राजपद की आवश्यकता महसूस की गई थी। यह सामाजिक सुरक्षा का आधार है।

86. (A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
रॉबर्ट नोजिक एक कट्टर उदारतावादी थे जिन्होंने न्यूनतम राज्य का समर्थन किया। उनका तर्क था कि व्यक्तियों के पास अपनी संपत्ति पर पूर्ण अधिकार है। यदि राज्य जनकल्याण के नाम पर धनी लोगों पर कर लगाता है, तो यह जबरन श्रम के समान है। नोजिक के अनुसार राज्य का कार्य केवल बाहरी और आंतरिक खतरों से सुरक्षा प्रदान करना होना चाहिए। किसी भी प्रकार का आर्थिक पुनर्वितरण व्यक्तिगत स्वतंत्रता और न्याय का उल्लंघन माना जाता है।

87. (D) अधिशेष मूल्य उत्पादित मूल्य और भुगतान किए गए वेतन के बीच का अंतर है।
कार्ल मार्क्स के अनुसार पूंजीपति श्रमिक को केवल उतना वेतन देते हैं जो उसके जीवित रहने के लिए आवश्यक है। परंतु श्रमिक अपने कार्य के दौरान उस वेतन से कहीं अधिक मूल्य की वस्तुओं का उत्पादन करता है। इस अतिरिक्त मूल्य या 'अधिशेष मूल्य' को पूंजीपति अपने लाभ के रूप में हड़प लेता है। मार्क्स ने इसे पूंजीवादी व्यवस्था में होने वाले शोषण का मूल कारण बताया। यही अधिशेष मूल्य पूंजी संचय का मुख्य आधार बनता है।

88. (A) समान बुनियादी स्वतंत्रता का सिद्धांत और भेद का सिद्धांत।
जॉन रॉल्स के अनुसार अज्ञानता के पर्दे के पीछे व्यक्ति न्याय के दो प्रमुख सिद्धांत चुनेंगे। प्रथम सिद्धांत प्रत्येक व्यक्ति को व्यापक बुनियादी स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। दूसरा सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि सामाजिक और आर्थिक असमानताएं केवल तभी स्वीकार्य हैं जब वे समाज के सबसे वंचित वर्ग के लिए हितकारी हों और सभी को समान अवसर प्राप्त हों। ये सिद्धांत निष्पक्षता और सामाजिक न्याय का मजबूत आधार तैयार करते हैं।

89. (A) P-2, Q-3, R-4, S-1
प्राचीन ग्रीक विचारकों ने राज्य को मानव विकास के लिए एक प्राकृतिक संस्था माना। सामाजिक अनुबंध के सिद्धांतकारों ने तर्क दिया कि सरकार की वैधता शासितों की सहमति पर आधारित होती है। उपयोगितावाद का केंद्र सुख को बढ़ाना और दुख को कम करना है। समकालीन उदारवाद राज्य को व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करने वाली एक आवश्यक बुराई के रूप में देखता है जो कम से कम हस्तक्षेप करे। ये विचारधाराएं राजनीतिक विज्ञान के विभिन्न चरणों को दर्शाती हैं।

90. (A) ध्यान भटकाने वाली वस्तुओं और निजी हितों के स्रोतों को समाप्त करना, जिससे राज्य के प्रति उनकी निष्ठा सुनिश्चित हो सके।
प्लेटो का मानना था कि परिवार और निजी संपत्ति व्यक्तियों में स्वार्थ की भावना पैदा करते हैं। संरक्षक वर्ग, जिसे राज्य की सुरक्षा का उत्तरदायित्व सौंपा गया है, उसे इन प्रलोभनों से मुक्त होना चाहिए। साम्यवाद की इस व्यवस्था के माध्यम से प्लेटो यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि शासकों का पूरा ध्यान केवल सार्वजनिक सेवा पर रहे। जब उनके पास अपना कोई निजी हित नहीं होगा, तभी वे राज्य की एकता को सर्वोपरि रख पाएंगे।

91. (D) जय प्रकाश नारायण
जय प्रकाश नारायण ने 'दलविहीन लोकतंत्र' का समर्थन किया जो गांधीवादी ग्राम स्वराज के समीप था। उनका मानना था कि दलीय राजनीति सत्ता के संघर्ष और भ्रष्टाचार का कारण बनती है। इसके विकल्प के रूप में उन्होंने विकेंद्रीकृत व्यवस्था का प्रस्ताव दिया जहाँ गाँव की ग्राम सभाओं के पास वास्तविक शक्ति हो। यह मॉडल नीचे से ऊपर की ओर लोकतंत्र के निर्माण पर जोर देता है, जहाँ जनता की सक्रिय भागीदारी से ही सच्चा स्वशासन संभव होता है।

92. (B) सर्वहारा वर्ग का नेतृत्व करने के लिए पेशेवर क्रांतिकारियों की एक लघु, अनुशासित और केंद्रीय रूप से संगठित पार्टी।
लेनिन का मानना था कि श्रमिक वर्ग अपने आप केवल व्यापारिक संघ वाली चेतना विकसित कर सकता है, जो क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए उन्होंने एक 'अग्रगामी दल' की आवश्यकता पर बल दिया। इस पार्टी में समर्पित और अनुशासित क्रांतिकारी होने चाहिए जो सर्वहारा वर्ग को राजनीतिक शिक्षा दें और क्रांति का नेतृत्व करें। यह दल क्रांति के लिए एक अत्यंत संगठित और प्रभावी उपकरण के रूप में कार्य करता है।

93. (A) 1, 3, 4, 2
इन भारतीय विचारकों का जन्म क्रम इस प्रकार है: महात्मा गांधी का जन्म 1869 में हुआ। वी.डी. सावरकर का जन्म 1883 में हुआ, जो हिंदुत्व के प्रमुख विचारक थे। एम.एन. रॉय का जन्म 1887 में हुआ, जिन्होंने मानवतावाद की यात्रा की। अंत में डॉ. बी.आर. अंबेडकर का जन्म 1891 में हुआ, जिन्होंने सामाजिक न्याय और संविधान निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाई। यह कालखंड भारतीय राजनीतिक विमर्श के उदय और उसके विकास को स्पष्ट करता है।

94. (D) एक ऐसा सामाजिक वातावरण जो व्यक्तियों को उनके नैतिक और बौद्धिक आत्म-साक्षात्कार को प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।
टी.एच. ग्रीन के अनुसार सामान्य हित केवल बहुमत की राय नहीं है, बल्कि वह स्थिति है जहाँ समाज के प्रत्येक सदस्य का कल्याण सामूहिक रूप से जुड़ा होता है। यह एक ऐसा साझा उद्देश्य है जो व्यक्तियों को स्वार्थ से ऊपर उठाकर सामाजिक उत्तरदायित्व की ओर ले जाता है। ग्रीन का मानना था कि जब लोग सामान्य हित के लिए कार्य करते हैं, तभी वे अपनी सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं और नैतिक जीवन संभव होता है।

NODIA

95. (A) शासन-कला या कूटनीति के चार साधन।
प्राचीन भारतीय राजनीति शास्त्र में राजा को अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए चार उपायों का उपयोग करने की सलाह दी गई है। 'साम' का अर्थ संधि करना है, 'दाम' का अर्थ धन देकर अनुकूल बनाना है, 'दंड' का अर्थ बल प्रयोग है, और 'भेद' का अर्थ शत्रु के पक्ष में फूट डालना है। कौटिल्य के अनुसार एक बुद्धिमान राजा को स्थिति की गंभीरता के अनुसार इनमें से सबसे उपयुक्त साधन का चयन करना चाहिए।

96. (B) पहले एक नागरिक समाज, और फिर एक सरकार या राजनीतिक समाज।
जॉन लॉक के अनुसार सामाजिक अनुबंध के दो चरण हैं। पहले चरण में लोग मिलकर एक नागरिक समाज का निर्माण करते हैं और अपने अधिकारों को स्वीकार करते हैं। दूसरे चरण में वे इस समाज की रक्षा के लिए एक सरकार की स्थापना करते हैं। सरकार केवल एक न्यासी के रूप में कार्य करती है जिसे जनता के अधिकारों की रक्षा का दायित्व सौंपा जाता है। यदि सरकार विफल होती है, तो समाज उसे बदलकर नई सरकार बना सकता है।

97. (A) केवल 1 और 2
एंटोनियो ग्राम्शी ने तर्क दिया कि पश्चिमी विकसित देशों में प्रत्यक्ष प्रहार के बजाय एक लंबी वैचारिक लड़ाई (स्थिति का युद्ध) आवश्यक है। उन्होंने 'जैविक बुद्धिजीवी' की अवधारणा दी जो अपने वर्ग की विचारधारा को समाज में फैलाते हैं। ग्राम्शी का मानना था कि क्रांति केवल आर्थिक स्थितियों पर निर्भर नहीं है, बल्कि इसके लिए सांस्कृतिक वर्चस्व को तोड़ना अनिवार्य है। उन्होंने वहां की विशिष्ट चुनौतियों और नागरिक समाज की मजबूती को स्पष्ट किया।

98. (A) यह परिवार और निजी संपत्ति की संस्थाओं को नष्ट कर देगा, जिन्हें वे स्वाभाविक और आवश्यक मानते थे।
अरस्तू ने प्लेटो के साम्यवाद की कड़ी आलोचना की क्योंकि उनका मानना था कि संपत्ति और परिवार मनुष्य की स्वाभाविक इच्छाएं हैं। निजी संपत्ति व्यक्ति को उत्तरदायी बनाती है और उसे परोपकार का अवसर प्रदान करती है। परिवार प्रेम और सामाजिक नैतिकता की प्राथमिक पाठशाला है। अरस्तू का तर्क था कि जिस वस्तु पर सबका अधिकार होता है, उसकी देखभाल कोई नहीं करता। उन्होंने शिक्षा के माध्यम से सुधार पर अधिक बल दिया।

99. (C) अपने आप में गलत और मानव सुधार की मुख्य बाधाओं में से एक।
जे.एस. मिल ने तर्क दिया कि महिलाओं को पुरुषों के अधीन रखना एक पुरानी और तर्कहीन प्रथा है। उनके अनुसार यह व्यवस्था न केवल महिलाओं के लिए अन्यायपूर्ण है, बल्कि यह समाज की आधी प्रतिभा को नष्ट करके पूरी मानवता की प्रगति को रोकती है। मिल ने कानून और विवाह में समानता की पुरजोर मांग की और स्पष्ट किया कि महिलाओं की स्वतंत्रता एक सभ्य तथा न्यायपूर्ण समाज के निर्माण के लिए अत्यंत आवश्यक है।

100. (D) किसान वर्ग
माओ जेदोंग ने मार्क्सवाद को चीनी परिस्थितियों में ढालते हुए यह महसूस किया कि वहां औद्योगिक श्रमिक वर्ग बहुत कम है। इसलिए उन्होंने क्रांति का मुख्य केंद्र गांवों को बनाया और किसानों को सबसे बड़ी क्रांतिकारी शक्ति के रूप में संगठित किया। उनका मानना था कि शोषित किसान अपनी विशाल संख्या के माध्यम से सामंती व्यवस्था को उखाड़ फेंक सकते हैं। यह विचार 'माओवाद' की एक विशिष्ट पहचान बना और इसने कई क्रांतियों को प्रभावित किया।

101. (A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
हॉब्स ने व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक शक्तिशाली और निरंकुश संप्रभु का समर्थन किया। इसके विपरीत, जॉन लॉक ने तर्क दिया कि सरकार की शक्तियां सीमित और जनहित के प्रति जवाबदेह होनी चाहिए। लॉक के अनुसार सरकार का एकमात्र उद्देश्य लोगों के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करना है। चूंकि सरकार जनता की सहमति से बनी एक 'न्यास' है, इसलिए यदि वह अधिकारों का हनन करती है, तो नागरिकों को उसे बदलने का पूर्ण अधिकार है।

102. (B) जी.डब्ल्यू.एफ. हेगेल
हेगेल ने राज्य को एक दिव्य और सर्वोच्च सत्ता के रूप में देखा। उनके अनुसार राज्य केवल एक राजनीतिक संस्था नहीं है, बल्कि यह सार्वभौमिक तर्क और नैतिकता का भौतिक प्रकटीकरण है। राज्य में ही व्यक्ति का अस्तित्व सार्थक होता है और वह अपनी वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त करता है। हेगेल का मानना था कि इतिहास की प्रगति का अंतिम लक्ष्य एक पूर्ण राज्य की प्राप्ति है जो 'परम आत्मा' की अभिव्यक्ति हो। यह विचार महत्वपूर्ण है।

103. (D) प्रत्येक गाँव एक आत्मनिर्भर और स्वशासित गणराज्य है।
महात्मा गांधी का ग्राम स्वराज का सपना सत्ता के पूर्ण विकेंद्रीकरण पर आधारित था। वे चाहते थे कि भारत के गाँव आर्थिक और राजनीतिक रूप से इतने सशक्त हों कि वे अपनी बुनियादी आवश्यकताओं के लिए बाहरी दुनिया पर निर्भर न रहें। ग्राम स्वराज में पंचायतें शासन का मुख्य केंद्र होती हैं और प्रत्येक ग्रामीण निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेता है। यह मॉडल छोटे समुदायों और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था पर जोर देता है।

104. (A) संभावित विजेता या महत्वाकांक्षी राजा को।
कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 'विजिगीषु' वह केंद्रीय पात्र है जो विजय की इच्छा रखता है और अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है। मंडल सिद्धांत का संपूर्ण विश्लेषण इसी राजा के इर्द-गिर्द घूमता है। कौटिल्य ने विजिगीषु को सलाह दी है कि वह अपनी सैन्य और कूटनीतिक शक्ति को कैसे बढ़ाए और सहयोगियों के साथ कैसे संबंध बनाए। यह शब्द एक सक्रिय और बुद्धिमान शासक की छवि को दर्शाता है जो राज्य के हितों के प्रति समर्पित है।

Downloaded from www.pdf.tube

105. (C) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।
मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार इतिहास का अंतिम लक्ष्य एक वर्गहीन और राज्यविहीन साम्यवादी समाज की स्थापना है। सर्वहारा वर्ग की तानाशाही इस गंतव्य तक पहुँचने का केवल एक संक्रमणकालीन चरण है। इस चरण के दौरान श्रमिक वर्ग राज्य की शक्ति का उपयोग पूंजीवादी अवशेषों को मिटाने के लिए करता है। मार्क्स का मानना था कि जब वर्गों का अंत हो जाएगा, तब राज्य की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी और वह स्वतः समाप्त हो जाएगा।

106. (A) वे विचारक जो सर्वहारा वर्ग जैसे मौलिक सामाजिक वर्ग से उभरते हैं और उनके हितों को व्यक्त करते हैं।
एंटोनियो ग्राम्शी ने जैविक बुद्धिजीवियों को उन विचारकों के रूप में परिभाषित किया जो अपने वर्ग के वास्तविक अनुभवों और संघर्षों से जुड़े होते हैं। ये बुद्धिजीवी अपने वर्ग को सांस्कृतिक और राजनीतिक दिशा प्रदान करते हैं और समाज में उनके वर्चस्व को स्थापित करने में सहायता करते हैं। ग्राम्शी के अनुसार सर्वहारा वर्ग को अपनी स्वयं की जैविक बुद्धिजीवी श्रेणी विकसित करनी होगी ताकि वह बुर्जुआ वर्ग के वैचारिक प्रभुत्व को चुनौती दे सके।

107. (D) समाज और व्यक्ति का एक शांतिपूर्ण, बहुआयामी परिवर्तन।
जय प्रकाश नारायण द्वारा प्रतिपादित संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य केवल सत्ता को हटाना नहीं था। वे समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार को मिटाकर एक नई व्यवस्था बनाना चाहते थे जिसमें व्यक्ति की नैतिकता और सामाजिक न्याय सर्वोपरि हो। यह सात क्रांतियों का समूह था जो शांतिपूर्ण माध्यमों से मानवीय जीवन के प्रत्येक पहलू में बदलाव लाना चाहती थी। इसमें छात्रों की सक्रिय भागीदारी पर बल दिया गया था ताकि लोकतंत्र को जीवंत बनाया जा सके।

108. (B) P-4, Q-3, R-2, S-1
डॉ. अंबेडकर ने 'जाति का विनाश' में जाति प्रथा की कड़ी आलोचना की। सावरकर ने 'हिंदुत्व' के माध्यम से हिंदू राष्ट्रवाद को परिभाषित किया। महात्मा गांधी की 'हिंद स्वराज' आधुनिक सभ्यता और औपनिवेशिक शासन की आलोचना प्रस्तुत करती है। अरविंदो घोष ने 'द लाइफ डिवाइन' में मानव चेतना के आध्यात्मिक विकास का दर्शन दिया। ये पुस्तकें भारत के राजनीतिक और सामाजिक चिंतन के विविध आयामों को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण आधार प्रदान करती हैं।

109. (C) जे.एस. मिल
जे.एस. मिल ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए मानवीय कार्यों को दो श्रेणियों में बांटा। 'स्व-विषयक' कार्य वे हैं जिनका प्रभाव केवल स्वयं व्यक्ति पर पड़ता है, जैसे खान-पान। इन कार्यों में राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। 'पर-विषयक' कार्य वे हैं जो दूसरों को प्रभावित या हानि पहुँचा सकते हैं। मिल के अनुसार केवल पर-विषयक कार्यों में ही राज्य द्वारा नियंत्रण लगाना उचित और न्यायसंगत माना जा सकता है। यह स्वतंत्रता का आधार है।

110. (D) व्यक्तिगत पूर्वाग्रह और आवेग लोगों को उनके अपने मामलों में खराब न्यायाधीश बनाते हैं।
जॉन लॉक के अनुसार यद्यपि प्राकृतिक अवस्था शांतिपूर्ण थी, लेकिन वहां एक निष्पक्ष निर्णायक का अभाव था। जब विवाद होते थे, तो लोग अपने हितों के प्रति पक्षपाती हो जाते थे और प्राकृतिक कानून को सही ढंग से लागू नहीं कर पाते थे। इसी असुविधा को दूर करने के लिए और न्याय के निष्पक्ष प्रशासन के लिए लोगों ने सामाजिक अनुबंध किया। इस प्रकार सरकार की स्थापना एक ऐसी तटस्थ सत्ता के रूप में हुई जो समाधान कर सके।

111. (A) समान क्षेत्र (राष्ट्र), समान जाति (जाति), और समान संस्कृति (संस्कृति)।
सावरकर के अनुसार हिंदुत्व के तीन आधारभूत स्तंभ हैं: भौगोलिक, जातीय और सांस्कृतिक। भौगोलिक रूप से व्यक्ति को भारत भूमि से जुड़ा होना चाहिए। जातीय दृष्टि से हिंदुओं में साझा रक्त का बोध होना चाहिए। सांस्कृतिक रूप से उन्हें भारत की प्राचीन परंपराओं और जीवन पद्धति को अपनाना चाहिए। सावरकर का मानना था कि जब ये तीनों तत्व एक साथ मिलते हैं, तभी एक सशक्त हिंदू राष्ट्र की पहचान निर्मित होती है जो हिंदुओं को जोड़ती है।

112. (A) केवल 1 और 2
अरस्तू ने अपनी पुस्तक में क्रांति के कारणों और प्रकारों का विस्तृत विश्लेषण किया है। उनके अनुसार समाज में व्याप्त असमानता या पूर्ण समानता की अतृप्त इच्छा ही अशांति और क्रांति का मूल कारण है। अरस्तू ने यह भी कहा कि शासन व्यवस्था या संविधान में होने वाला कोई भी छोटा या बड़ा बदलाव क्रांति की श्रेणी में आता है। हालांकि वे निरंकुश शासन को सबसे घटिया और अस्थिर व्यवस्था मानते थे, जो समाज के लिए हानिकारक है।

113. (B) जॉन लॉक
जॉन लॉक का राजनीतिक दर्शन इस सिद्धांत पर टिका है कि किसी भी सरकार की वैधता केवल शासितों की सहमति से ही प्राप्त होती है। राजा या सरकार के पास कोई दैवीय अधिकार नहीं है। लोग स्वेच्छा से एक अनुबंध के माध्यम से अपनी शक्ति सरकार को सौंपते हैं ताकि उनके अधिकारों की रक्षा हो सके। यदि सरकार जनमत की उपेक्षा करती है या सहमति खो देती है, तो उसका शासन करने का नैतिक अधिकार स्वतः ही समाप्त हो जाता है।

114. (A) निजी या गैर-राज्य संस्थान जैसे चर्च, विद्यालय और ट्रेड यूनियन।
एंटोनियो ग्राम्शी ने नागरिक समाज को उन संस्थानों के क्षेत्र के रूप में देखा जहाँ राज्य प्रत्यक्ष बल का प्रयोग नहीं करता, बल्कि वैचारिक प्रभुत्व स्थापित करता है। यहाँ परिवार, मीडिया और विद्यालय लोगों की सोच को आकार देते हैं। ग्राम्शी के अनुसार शासक वर्ग इसी क्षेत्र में अपने वर्चस्व का निर्माण करता है, जिससे लोग व्यवस्था को बिना विरोध के स्वीकार कर लेते हैं। क्रांति के लिए इस नागरिक समाज के भीतर वैचारिक संघर्ष अनिवार्य है।

NODIA

115. (C) एम.एन. रॉय
एम.एन. रॉय ने अपने उत्तरवर्ती जीवन में मौलिक मानवतावाद का दर्शन प्रस्तुत किया। उन्होंने तर्क दिया कि राजनीतिक दलों और सत्ता के संघर्ष से हटकर व्यक्ति की तर्कशक्ति और स्वतंत्रता पर ध्यान देना चाहिए। उनका मानना था कि समाज का वास्तविक उद्धार तभी संभव है जब प्रत्येक मनुष्य स्वयं को स्वतंत्र महसूस करे। रॉय ने दलविहीन लोकतंत्र का समर्थन किया और तर्क दिया कि शक्ति को ग्राम स्तर की जन समितियों के माध्यम से विकेंद्रीकृत किया जाना चाहिए।

116. (D) उच्च सुखों के गुणात्मक श्रेष्ठता।
जे.एस. मिल का यह प्रसिद्ध कथन बेंथम के मात्रात्मक उपयोगितावाद की आलोचना है। मिल ने तर्क दिया कि मानसिक और बौद्धिक सुख शारीरिक सुखों की तुलना में कहीं अधिक मूल्यवान होते हैं। एक जागरुक और शिक्षित मनुष्य भले ही असंतुष्ट हो, उसका जीवन एक अज्ञानी व्यक्ति के जीवन से श्रेष्ठ है। यह विचार उपयोगितावाद को केवल भौतिक आनंद से ऊपर उठाकर मानवीय गरिमा के साथ जोड़ता है, जिससे यह एक उच्च नैतिक दर्शन बनता है।

117. (A) 2, 1, 3, 4
इन पुस्तकों का प्रकाशन क्रम इस प्रकार है: मैकियावेली की 'द प्रिंस' 1532 में प्रकाशित हुई। हॉब्स की 'लेविआथन' 1651 में आई, जिसने पूर्ण संप्रभुता का सिद्धांत दिया। जॉन लॉक की 'टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट' 1689 में प्रकाशित हुई, जो उदारवाद का आधार बनी। अंत में रूसो की 'द सोशल कॉन्ट्रैक्ट' 1762 में आई, जिसने सामान्य इच्छा का विचार दिया। यह क्रम राजनीतिक सिद्धांतों के क्रमिक विकास की कहानी कहता है और अत्यंत महत्वपूर्ण है।

118. (B) 'भाग्य' मानवीय मामलों के लगभग आधे भाग को नियंत्रित करता है, जबकि 'वीरता' शेष को आकार दे सकती है।
मैकियावेली के अनुसार 'भाग्य' एक विनाशकारी नदी के समान है जिसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता, लेकिन 'वीरता' या शासक का कौशल उसके प्रभाव को कम कर सकता है। उनका मानना था कि सफलता केवल भाग्य पर निर्भर नहीं है; एक साहसी और बुद्धिमान राजकुमार अपनी तैयारी से प्रतिकूल परिस्थितियों को भी अपने अनुकूल मोड़ सकता है। यह सिद्धांत मानवीय प्रयासों और रणनीतिक बुद्धिमानी को राजनीति में सफलता का महत्वपूर्ण कारक मानता है।

119. (D) सहायक (सैनिक)
प्लेटो के आदर्श राज्य में 'सहायक' या सैनिक वर्ग का मुख्य गुण साहस है। इस वर्ग का उत्तरदायित्व राज्य की बाहरी शत्रुओं से रक्षा करना और आंतरिक रूप से व्यवस्था बनाए रखने में शासकों की सहायता करना है। प्लेटो के अनुसार जिस व्यक्ति की आत्मा में साहस का तत्व प्रधान होता है, उसे कठोर प्रशिक्षण के बाद इस वर्ग में शामिल किया जाना चाहिए। ये लोग दार्शनिक राजाओं के आदेशों का पालन करते हैं और राज्य के लिए समर्पित रहते हैं।

120. (A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
डॉ. बी.आर. अंबेडकर का दृढ़ विश्वास था कि संयुक्त निर्वाचक मंडल में दलितों के प्रतिनिधि हिंदू बहुसंख्यकों के प्रभाव में रहेंगे, जिससे उनकी वास्तविक आवाज दब जाएगी। उन्होंने तर्क दिया कि दलितों को अपने स्वयं के प्रतिनिधियों को चुनने के लिए पृथक मतदान का अधिकार मिलना चाहिए ताकि उनकी समस्याओं को बिना किसी दबाव के उठाया जा सके। पूना पैक्ट से पहले यह मुद्दा अंबेडकर और गांधी के बीच गहरे वैचारिक मतभेद का प्रमुख कारण बना था।

121. (C) समाज को अराजकता में गिरने से रोकना।
शांति पर्व के अनुसार दंडनीति राज्य का वह आधार है जो अधर्म पर नियंत्रण रखता है और न्याय सुनिश्चित करता है। भीष्म के अनुसार यदि दंड की शक्ति न हो, तो समाज में बलवान व्यक्ति निर्बलों का शोषण करेंगे और चारों ओर भय का वातावरण व्याप्त हो जाएगा। दंड केवल सजा नहीं है, बल्कि यह वह अनुशासन है जो सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित रखता है। इसके माध्यम से राजा प्रजा के जीवन और संपत्ति की रक्षा करने में समर्थ होता है।

122. (A) निजी, स्वार्थी हितों का योग।
रूसो ने 'सभी की इच्छा' और 'सामान्य इच्छा' में स्पष्ट भेद किया है। 'सभी की इच्छा' केवल नागरिकों के व्यक्तिगत और निजी हितों का एक संग्रह है, जिसमें समाज के समग्र कल्याण की कमी हो सकती है। इसके विपरीत 'सामान्य इच्छा' केवल उन उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित करती है जो संपूर्ण समुदाय के लिए हितकारी हों। रूसो का मानना था कि लोकतंत्र की सफलता के लिए व्यक्तियों को अपने संकीर्ण स्वार्थों को छोड़कर सामान्य इच्छा के मार्गदर्शन में कार्य करना चाहिए।

123. (B) अवसर की उचित समानता।
जॉन रॉल्स के न्याय के दूसरे सिद्धांत के अनुसार सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को दो शर्तों को पूरा करना चाहिए। पहली शर्त 'अवसर की उचित समानता' है, जिसका अर्थ है कि पद और स्थान सभी के लिए समान रूप से खुले होने चाहिए। दूसरी शर्त 'भेद का सिद्धांत' है जो सबसे कम सुविधा प्राप्त लोगों के कल्याण पर केंद्रित है। रॉल्स के अनुसार स्वतंत्रता के बाद अवसर की समानता एक न्यायपूर्ण समाज के निर्माण के लिए अनिवार्य शर्त है।

124. (B) एक ही दल द्वारा नियंत्रित अत्यधिक केंद्रीकृत राज्य
एम.एन. रॉय की मौलिक लोकतंत्र अवधारणा का मुख्य आधार सत्ता का विकेंद्रीकरण और व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। वे दलीय राजनीति के सख्त विरोधी थे क्योंकि उनके अनुसार दल सत्ता हथियाने का माध्यम बन जाते हैं। रॉय ने एक ऐसी व्यवस्था का प्रस्ताव दिया जहाँ पिरामिड की तरह नीचे से ऊपर की ओर शक्ति प्रवाहित हो और 'जन समितियों' के माध्यम से जनता शासन में भाग ले। वे किसी भी प्रकार की केंद्रीकृत तानाशाही को लोकतंत्र के लिए घातक मानते थे।

Click Here to Buy book on Amazon

125. (C) कुछ करने या आनंद लेने योग्य कार्य करने या आनंद लेने की एक सकारात्मक क्षमता।
टी.एच. ग्रीन के अनुसार स्वतंत्रता केवल कानून के अभाव या बाहरी प्रतिबंधों से मुक्ति नहीं है। यह एक सकारात्मक शक्ति है जो व्यक्ति को अपनी क्षमताओं का विकास करने और समाज में योगदान देने के योग्य बनाती है। ग्रीन का मानना था कि सच्ची स्वतंत्रता का अर्थ उन कार्यों को करना है जो वास्तव में करने योग्य और नैतिक हों। राज्य का कार्य इस सकारात्मक स्वतंत्रता के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना है ताकि प्रत्येक नागरिक जी सके।

126. (C) P-4, Q-1, R-2, S-3
रॉबर्ट नोज़िक ने अपनी हकदारी की अवधारणा में संपत्ति के न्यायपूर्ण वितरण पर बल दिया। जॉन रॉल्स ने 'निष्पक्षता के रूप में न्याय' का सिद्धांत दिया जो अज्ञानता के पर्दे पर आधारित है। माइकल सैंडेल ने उदारवादी व्यक्तिवाद की आलोचना करते हुए 'सन्निहित स्व' के महत्व को रेखांकित किया। एंटोनियो ग्राम्शी ने वैचारिक वर्चस्व के माध्यम से यह समझाया कि कैसे शासक वर्ग विचारों के माध्यम से समाज पर अपना प्रभुत्व बनाए रखता है। ये चारों अवधारणाएं राजनीतिक दर्शन के आधारभूत तत्व हैं।

127. (A) अनुबंध का पक्षकार नहीं है और उसके पास पूर्ण, असीमित शक्ति है।
थॉमस हॉब्स के अनुसार संप्रभु उस सामाजिक अनुबंध का हिस्सा नहीं है जो लोगों ने आपस में किया है। चूंकि वह अनुबंध की शर्तों से ऊपर है, इसलिए उसकी शक्ति पर कोई कानूनी अंकुश नहीं लगाया जा सकता। लेविआथन को पूर्ण संप्रभुता प्रदान की गई है ताकि वह समाज को प्राकृतिक अवस्था की अराजकता से बचा सके। प्रजा का एकमात्र कर्तव्य संप्रभु की आज्ञा का पालन करना है, क्योंकि उसकी सत्ता ही समाज में शांति का एकमात्र आधार है।

128. (B) अनैतिकता और भौतिकवाद।
'हिंद स्वराज' में महात्मा गांधी ने आधुनिक पश्चिमी सभ्यता को 'शैतानी सभ्यता' कहा है क्योंकि यह केवल भौतिक सुख और शारीरिक भोग पर आधारित है। उनका तर्क था कि अस्पताल और वकील जैसे आधुनिक संस्थान मनुष्य को नैतिक रूप से पंगु बना रहे हैं और उसे आत्म-संयम से दूर ले जा रहे हैं। गांधी जी के अनुसार सच्ची सभ्यता वह है जो मनुष्य को कर्तव्य के मार्ग पर चलाए और उसके चरित्र का निर्माण करे, न कि इच्छाओं को बढ़ाए।

129. (B) केवल 1
जॉन लॉक ने प्राकृतिक अवस्था का चित्रण हॉब्स के विपरीत अत्यंत सकारात्मक रूप में किया है। लॉक के अनुसार इस अवस्था में मनुष्य प्राकृतिक कानून के अधीन रहते थे और शांति तथा सद्भावना का वातावरण था। लोग अपने जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकारों का आनंद लेते थे। हॉब्स के लिए यह अवस्था निरंतर युद्ध की थी, जबकि रूसो के लिए यह सादगी वाली स्थिति थी। लॉक का यह दृष्टिकोण उदारवादी सिद्धांतों और व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा का आधार बना।

130. (A) एक दैवीय वास्तविकता, एक आध्यात्मिक ऊर्जा जिसे अनुभव करने की आवश्यकता थी।
अरविंदो घोष के अनुसार भारत केवल मिट्टी का एक टुकड़ा या भौगोलिक इकाई नहीं है, बल्कि वह एक 'मातृशक्ति' और आध्यात्मिक ऊर्जा है। उन्होंने राष्ट्रवाद को एक धर्म माना जो ईश्वर की इच्छा से प्रेरित है। आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का अर्थ था कि भारत की स्वतंत्रता केवल राजनीतिक मुक्ति नहीं, बल्कि मानवता के आध्यात्मिक उद्धार के लिए आवश्यक है। अरविंदो का मानना था कि भारत का पुनरुत्थान विश्व को उच्च चेतना की ओर ले जाने के लिए अनिवार्य है।

131. (C) जॉन लॉक
जॉन लॉक के राजनीतिक दर्शन में जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति को 'प्राकृतिक अधिकार' माना गया है जिन्हें कोई भी सरकार छीन नहीं सकती। लॉक का मानना था कि मनुष्य इन अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ही नागरिक समाज और सरकार का निर्माण करते हैं। सरकार की वैधता का एकमात्र मापदंड इन अधिकारों की रक्षा करना है। यदि कोई शासन इन मौलिक अधिकारों का हनन करता है, तो जनता के पास उसके विरुद्ध विद्रोह करने का प्राकृतिक अधिकार होता है।

132. (D) वास्तविक उपाय उन धार्मिक धारणाओं को नष्ट करना है जिन पर जाति आधारित है।
डॉ. अंबेडकर का तर्क था कि जाति व्यवस्था को हिंदू धर्मशास्त्रों द्वारा धार्मिक मान्यता प्राप्त है। जब तक लोग शास्त्रों की पवित्रता और उनमें निहित वर्ण व्यवस्था के सिद्धांतों में विश्वास करना बंद नहीं करेंगे, तब तक जाति को पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने अंतर-जातीय विवाह को एक समाधान माना, लेकिन उनका मानना था कि इसका मूल कारण उन धार्मिक विश्वासों में छिपा है जो असमानता को बढ़ावा देते हैं और शोषण को पवित्र बनाते हैं।

133. (C) नागरिकों को अच्छा जीवन प्राप्त करने में सक्षम बनाना।
अरस्तू के अनुसार राज्य केवल जीवन की रक्षा के लिए अस्तित्व में आया, लेकिन वह 'श्रेष्ठ जीवन' की प्राप्ति के लिए बना हुआ है। राज्य एक प्राकृतिक संस्था है जिसका उद्देश्य नागरिकों में सद्गुणों का विकास करना और उन्हें पूर्ण आत्म-साक्षात्कार के योग्य बनाना है। एक सुव्यवस्थित राज्य में ही व्यक्ति अपनी तर्कसंगत क्षमताओं का प्रयोग कर सकता है और वास्तविक प्रसन्नता प्राप्त कर सकता है। राज्य का लक्ष्य केवल भौतिक सुरक्षा नहीं, बल्कि नागरिकों का नैतिक उत्कर्ष है।

134. (B) कम्युनिस्ट समाज (उच्च चरण)
कार्ल मार्क्स के अनुसार साम्यवाद के उच्च चरण में जब उत्पादन के साधनों का पूर्ण विकास हो जाएगा, तब वितरण का आधार कार्य नहीं बल्कि आवश्यकता होगी। इस अवस्था में प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार समाज में योगदान देगा और अपनी जरूरतों के अनुसार संसाधन प्राप्त करेगा। यह एक ऐसे आदर्श समाज की कल्पना है जहाँ अभाव पूरी तरह समाप्त हो जाएगा और मानवीय श्रम केवल विवशता नहीं बल्कि सृजन का एक आनंददायक माध्यम बन जाएगा।

NODIA

135. (C) केवल 2 और 3
मैकियावेली ने 'द प्रिंस' में शासक को सलाह दी कि उसे वास्तविकतावादी होना चाहिए। यद्यपि गुणी होना अच्छी बात है, लेकिन सत्ता बनाए रखने के लिए राजकुमार को धोखे और क्रूरता का उपयोग करने में संकोच नहीं करना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि प्रेम चंचल होता है, जबकि भय दंड की संभावना के कारण अधिक स्थायी होता है। इसलिए एक राजा को प्रेम किए जाने के बजाय डरा हुआ होना चाहिए ताकि प्रजा उसके नियंत्रण में रहे और शासन स्थिर रहे।

136. (A) बुद्धिजीवियों के एक अग्रगामी दल द्वारा बाहर से श्रमिक वर्ग में लाई जानी चाहिए।
लेनिन का मानना था कि श्रमिक वर्ग अपने दैनिक संघर्षों से केवल अपनी मजदूरी में सुधार की मांग कर सकता है। वास्तविक राजनीतिक चेतना उनमें स्वतः उत्पन्न नहीं हो सकती। इसके लिए एक संगठित दल की आवश्यकता है जो सिद्धांतों को गहराई से समझता हो और श्रमिकों को व्यापक राजनीतिक लक्ष्य की ओर निर्देशित करे। यह 'अग्रगामी दल' क्रांति का इंजन है जो श्रमिक वर्ग को शोषणकारी व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए प्रशिक्षित और संगठित करता है।

137. (C) कौटिल्य का अर्थशास्त्र
कौटिल्य के अर्थशास्त्र में सप्तांग सिद्धांत का विस्तृत वर्णन मिलता है जो राज्य की संरचना को स्पष्ट करता है। ये सात अंग हैं: स्वामी (राजा), अमात्य (मंत्री), जनपद (क्षेत्र), दुर्ग (किला), कोष (खजाना), दंड (सेना) और मित्र (सहयोगी)। कौटिल्य ने इन अंगों की तुलना शरीर के विभिन्न अंगों से की है और बताया है कि राज्य की सुदृढ़ता इन सातों के बीच तालमेल पर निर्भर करती है। यह प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन का अत्यंत महत्वपूर्ण आधारभूत ढांचा है।

138. (A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
जे.एस. मिल लोकतंत्र को सरकार का सबसे अच्छा रूप मानते थे, लेकिन उन्हें डर था कि अज्ञानी बहुमत शिक्षित अल्पसंख्यकों के अधिकारों को कुचल सकता है। इस समस्या के समाधान के लिए उन्होंने 'बहुल मतदान' का सुझाव दिया जहाँ शिक्षित व्यक्तियों के मत का मूल्य अधिक हो। वे चाहते थे कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में बुद्धिमानी और तर्क का प्रभाव बना रहे। मिल का यह दृष्टिकोण लोकतांत्रिक मूल्यों और व्यक्तिगत योग्यता के बीच संतुलन बनाने का प्रयास था।

139. (D) जनता के बिखरे हुए विचारों को संकलित करना और उन्हें नीति के रूप में वापस करना।
माओ जेदोंग का 'जन-पंक्ति' का सिद्धांत नेतृत्व और जनता के बीच निरंतर संवाद की प्रक्रिया है। इसमें कैडरों को पहले जनता के बीच जाकर उनके अनुभवों को समझना होता है। फिर पार्टी उन विचारों को मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ व्यवस्थित और परिष्कृत करती है। अंत में इन परिष्कृत विचारों को नीतियों के रूप में जनता के पास ले जाया जाता है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि पार्टी नीतियां जमीनी हकीकत से जुड़ी रहें और जनता का विश्वास बना रहे।

140. (B) जी.डब्ल्यू.एफ. हेगेल
हेगेल ने समाज को तीन स्तरों पर विभाजित किया: परिवार, नागरिक समाज और राज्य। उनके अनुसार नागरिक समाज आर्थिक हितों और व्यक्तिगत आवश्यकताओं का क्षेत्र है जहाँ लोग अपने स्वार्थ के लिए एक-दूसरे से जुड़ते हैं। हेगेल का मानना था कि नागरिक समाज के अंतर्विरोधों का समाधान केवल राज्य में ही संभव है। राज्य वह सर्वोच्च संस्था है जो सभी व्यक्तिगत हितों को सामान्य हित में समाहित करती है और समाज को एकता तथा नैतिकता प्रदान करती है।

141. (C) एक न्यूनतम, नाइट-वॉचमैन राज्य
रॉबर्ट नोज़िक ने अपनी पुस्तक में तर्क दिया कि राज्य का अस्तित्व केवल सुरक्षा और न्याय प्रदान करने के लिए होना चाहिए। वे कल्याणकारी राज्य की नीतियों जैसे आय के पुनर्वितरण का विरोध करते हैं, क्योंकि इनमें कुछ लोगों की मदद के लिए दूसरों की संपत्ति का जबरन उपयोग किया जाता है। नोज़िक के अनुसार व्यक्ति स्वयं का स्वामी है और राज्य को उसकी सहमति के बिना उसके निजी संसाधनों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। यह उदारतावाद का मुख्य आधार है।

142. (D) प्लेटो की पद्धति निगमनात्मक और आदर्शवादी थी, जबकि अरस्तू की अधिक अनुभवजन्य और पर्यवेक्षणात्मक थी।
प्लेटो ने अमूर्त विचारों और 'शुभ के स्वरूप' से शुरुआत की और एक कल्पनाशील आदर्श राज्य का खाका तैयार किया। इसके विपरीत अरस्तू ने मौजूदा 158 संविधानों का अध्ययन किया और अपने निष्कर्षों को वास्तविक तथ्यों पर आधारित किया। अरस्तू को अक्सर राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है क्योंकि उन्होंने राजनीति को वैज्ञानिक तरीके से समझने का प्रयास किया। जबकि प्लेटो का दृष्टिकोण दार्शनिक था, अरस्तू का दृष्टिकोण अधिक व्यावहारिक और तुलनात्मक शोध पर आधारित था।

143. (A) जय प्रकाश नारायण - आध्यात्मिक राष्ट्रवाद
आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का विचार मुख्य रूप से अरविंदो घोष से जुड़ा है, जिन्होंने राष्ट्र को एक दिव्य माँ के रूप में देखा। जय प्रकाश नारायण 'संपूर्ण क्रांति' और 'दलविहीन लोकतंत्र' के विचारों के लिए जाने जाते हैं। महात्मा गांधी ने न्यासिता का आर्थिक मॉडल दिया, एम.एन. रॉय ने मौलिक मानवतावाद का प्रतिपादन किया और डॉ. अंबेडकर ने जाति के विनाश की मांग की। जय प्रकाश नारायण का योगदान मुख्य रूप से समाजवादी और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के क्षेत्र में रहा है।

NODIA

144. (B) एक गणराज्य जिसमें लोग संपरभु हैं और सीधे कानून बनाते हैं।
रूसो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के प्रबल समर्थक थे। उनके अनुसार संप्रभुता को न तो विभाजित किया जा सकता है और न ही किसी प्रतिनिधि को सौंपा जा सकता है। एक वैध राज्य वही है जहाँ नागरिक स्वयं सभाओं में एकत्रित होकर सामान्य इच्छा के आधार पर कानून बनाते हैं। रूसो का गणराज्य स्वतंत्रता और समानता के आदर्शों पर टिका है, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति कानून का निर्माता भी है और उसका पालन करने वाला नागरिक भी। वे इसे ही वास्तविक स्वतंत्रता मानते थे।

145. (B) जैसे मधुमक्खी पुष्पों को क्षति पहुँचाए बिना उनसे मधु एकत्र करती है।
शांति पर्व में कराधान के विषय में अत्यंत विवेकपूर्ण सलाह दी गई है। इसके अनुसार राजा को कर इस तरह वसूलना चाहिए कि प्रजा पर उसका भार महसूस न हो और उनकी आर्थिक स्थिति दुर्बल न हो। जैसे मधुमक्खी पुष्प से रस लेती है और पुष्प खिला रहता है, वैसे ही राजा को केवल उतना ही कर लेना चाहिए जिससे राज्य का कोष भी भरे और प्रजा की समृद्धि बनी रहे। यह कर नीति न्यायसंगत और विकासोन्मुखी शासन का एक प्रमुख प्रतीक है।

146. (A) उत्पादन की शक्तियों और उत्पादन के संबंधों के बीच।
मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद के भीतर एक गहरा अंतर्विरोध होता है। एक ओर तकनीक और उत्पादन की शक्तियां विकसित होती हैं, दूसरी ओर उत्पादन के संबंध (जैसे निजी संपत्ति) पुराने और शोषणकारी बने रहते हैं। यह असंतुलन आर्थिक संकटों और वर्ग संघर्ष को जन्म देता है। जब उत्पादन के संबंध विकास के मार्ग में बाधा बन जाते हैं, तो समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन की स्थिति उत्पन्न होती है। यही द्वंद्व इतिहास की प्रगति का मुख्य चालक माना जाता है।

147. (A) 1, 3, 4, 2
राजनीतिक विचारधाराओं का ऐतिहासिक क्रम इस प्रकार है: प्राचीन ग्रीक विचार ईसा पूर्व काल के हैं। यूरोपीय प्रबोधन विचार 17वीं और 18वीं शताब्दी में आए, जिसने व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल दिया। उपयोगितावाद 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में बेंथम के साथ उभरा। समकालीन समुदायवाद 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उदारवाद की प्रतिक्रिया के रूप में विकसित हुआ। यह क्रम मानव समाज के राजनीतिक विमर्श के क्रमिक परिपक्व होने की यात्रा को स्पष्ट रूप से दर्शाता है।

148. (D) "सत्य की शक्ति" या "आत्मिक शक्ति," विरोध की एक अहिंसक पद्धति।
सत्याग्रह गांधी जी का सबसे शक्तिशाली राजनीतिक और नैतिक हथियार था। इसका अर्थ है सत्य के मार्ग पर दृढ़ रहना और विरोधी को कष्ट पहुँचाने के बजाय स्वयं कष्ट सहकर उसका हृदय परिवर्तन करना। सत्याग्रह में घृणा या हिंसा का कोई स्थान नहीं है। यह आत्मा की शक्ति का प्रयोग है जो शारीरिक बल से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। गांधी जी का मानना था कि अहिंसक प्रतिरोध के माध्यम से सबसे शक्तिशाली साम्राज्य को भी झुकाया जा सकता है।

149. (A) P-3, Q-2, R-1, S-4
कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में राज्य के विभिन्न अंगों को स्पष्ट भूमिका दी गई है। 'अमात्य' राज्य की प्रशासनिक मशीनरी या मंत्रियों का समूह है। 'जनपद' राज्य के भौगोलिक क्षेत्र और वहां रहने वाली जनता को संदर्भित करता है। 'दुर्ग' राज्य की सुरक्षा के लिए बनाए गए किलों का प्रतीक है। 'कोष' राज्य के आर्थिक आधार या संचित धन को दर्शाता है। ये चारों तत्व राज्य के सुचारु संचालन और उसकी स्थिरता के लिए अनिवार्य अंग माने गए हैं।

150. (B) एक ऐसा स्व जो चयन करने के लिए अपने इतिहास, समुदाय और मूल्यों से पृथक खड़ा हो सकता है।
माइकल सैंडेल का तर्क है कि उदारवादी न्याय सिद्धांत व्यक्ति को एक खाली स्लेट की तरह देखते हैं। वे मानते हैं कि व्यक्ति अपनी सामाजिक पृष्ठभूमि और परंपराओं से अलग होकर स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकता है। सैंडेल इसे 'असंलग्न स्व' कहते हैं और इसकी आलोचना करते हैं। उनके अनुसार हमारी पहचान हमारे समुदाय के मूल्यों और इतिहास से इतनी गहराई से जुड़ी होती है कि हम उनसे पूरी तरह अलग होकर कोई चुनाव नहीं कर सकते।

151. (C) केवल 1 और 3
हॉब्स के अनुसार लेविआथन या संप्रभु एक ऐसी शक्ति है जो शांति बनाए रखने के लिए असीमित अधिकार रखती है। वह प्रजा के साथ किसी अनुबंध में नहीं बंधा है, इसलिए उसकी किसी भी कार्रवाई को 'अन्यायपूर्ण' नहीं कहा जा सकता। संप्रभु की शक्ति को विभाजित नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे राज्य पुनः अराजकता की ओर बढ़ जाएगा। हॉब्स ने उसे एक 'नश्वर ईश्वर' की संज्ञा दी है जिसके प्रति प्रजा को पूर्ण आज्ञाकारिता रखनी चाहिए ताकि समाज सुरक्षित रहे।

152. (A) सामाजिक उदारवाद या नया उदारवाद
टी.एच. ग्रीन ने शास्त्रीय उदारवाद की नकारात्मक स्वतंत्रता की आलोचना की और सकारात्मक स्वतंत्रता का विचार दिया। उन्होंने तर्क दिया कि केवल कानून की अनुपस्थिति स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि राज्य को शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं प्रदान करके व्यक्ति को वास्तव में स्वतंत्र बनाना चाहिए। ग्रीन के इन विचारों ने उदारवाद को सामाजिक न्याय और सामूहिक कल्याण के साथ जोड़ा। इसी कारण उन्हें 'नए उदारवाद' का प्रणेता माना जाता है, जिसने कल्याणकारी राज्य की नींव रखी।

153. (C) शासक सर्वाधिक बुद्धिमान होते हैं, सैनिक सर्वाधिक साहसी होते हैं, और उत्पादक अपना कार्य करते हैं।
प्लेटो के अनुसार न्याय वह गुण है जो राज्य के सभी वर्गों में सद्भाव बनाए रखता है। एक न्यायपूर्ण राज्य में प्रत्येक वर्ग—शासक, सैनिक और उत्पादक—अपनी विशिष्ट क्षमताओं के अनुसार कार्य करता है और दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता। दार्शनिक राजा विवेक के साथ शासन करते हैं, सैनिक साहस के साथ सुरक्षा करते हैं और उत्पादक संयम के साथ आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। यह कार्यात्मक विशेषज्ञता ही प्लेटो के आदर्श राज्य की आधारशिला है।

154. (A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
जेरेमी बेंथम का मानना था कि कानून को तर्कसंगत और उपयोगितावादी सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। उन्होंने तत्कालीन ब्रिटिश कानूनी व्यवस्था की आलोचना की क्योंकि वह जटिल और प्राचीन परंपराओं पर आधारित थी। बेंथम ने 'कानून के संहिताकरण' की वकालत की ताकि सामान्य जनता भी कानून को आसानी से समझ सके। उनके अनुसार कानून का एकमात्र उद्देश्य अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख सुनिश्चित करना होना चाहिए, न कि पुरानी रूढ़ियों का पालन करना।

Downloaded from www.pdf.tube

STUDYING FROM PDFs?

THINK AGAIN.

If you are studying only from PDFs,
you are wasting valuable time.

Research shows that learning from

PRINTED BOOKS has up to

4× HIGHER RETENTION

than studying from screens.

PRINT BOOK = BETTER MEMORY

PDF = LOWER RETENTION

Those who study from **PRINTED BOOKS**
move **AHEAD.**

Others are left **BEHIND**
in competition.

In competitive exams,
being average is not enough.

STAY ONE STEP AHEAD.

155. (D) समुदायवादी परिषदों की एक जमीनी स्तर की व्यवस्था।
जय प्रकाश नारायण के अनुसार दलीय राजनीति जनता को विभाजित करती है और सत्ता का केंद्रीकरण करती है। उनके दलविहीन लोकतंत्र का मॉडल ग्राम सभाओं और स्थानीय परिषदों पर आधारित था जहाँ लोग बिना किसी दलीय दबाव के निर्णय ले सकें। वे चाहते थे कि राजनीतिक शक्ति पिरामिड की तरह ऊपर से नीचे नहीं, बल्कि गांवों से केंद्र की ओर प्रवाहित हो। यह व्यवस्था प्रत्यक्ष भागीदारी और सामूहिक निर्णय लेने की प्रक्रिया के माध्यम से लोकतंत्र को अधिक वास्तविक बनाती है।

156. (B) युद्ध की स्थिति।
थॉमस हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था या 'युद्ध की स्थिति' में कोई सार्वभौमिक न्याय या कानून नहीं होता। वहां केवल बल और धोखाधड़ी ही दो मुख्य शक्तियां होती हैं जिनका उपयोग मनुष्य अपने अस्तित्व को बचाने के लिए करता है। यह एक ऐसी अराजक स्थिति है जहाँ सुरक्षा का पूर्ण अभाव होता है। हॉब्स का तर्क है कि इसी 'हर किसी का हर किसी के विरुद्ध युद्ध' की स्थिति से बचने के लिए नागरिक समाज का निर्माण और संप्रभु सत्ता की स्थापना अनिवार्य है।

157. (C) माइकल वाल्ज़र
माइकल वाल्ज़र एक प्रमुख समुदायवादी दार्शनिक हैं जिन्होंने अपनी पुस्तक 'स्फेयर्स ऑफ जस्टिस' के माध्यम से उदारवाद के सार्वभौमिक न्याय के सिद्धांतों को चुनौती दी। उनका तर्क है कि न्याय के नियम अलग-अलग संस्कृतियों और सामाजिक संदर्भों के अनुसार भिन्न होने चाहिए। वाल्ज़र के अनुसार न्याय की कोई एक परिभाषा सभी समाजों पर थोपी नहीं जा सकती। रॉबर्ट नोजिक, जॉन रॉल्स और फ्रेडरिक हायेक मुख्य रूप से उदारवादी या उदारतावादी परंपराओं से जुड़े हुए विचारक माने जाते हैं।

158. (D) द कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो
'कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो' की यह प्रसिद्ध शुरुआती पंक्ति मार्क्सवादी विचारधारा का मूल सार प्रस्तुत करती है। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स ने तर्क दिया कि मानव इतिहास का विकास उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण को लेकर होने वाले निरंतर संघर्ष का परिणाम है। दास और स्वामी, सामंत और किसान, और अंततः पूंजीपति और सर्वहारा के बीच का यह वर्ग संघर्ष ही ऐतिहासिक परिवर्तन का मुख्य कारण रहा है। मार्क्स का मानना था कि यह संघर्ष अंततः वर्गहीन समाज के साथ समाप्त होगा।

159. (A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
एंटोनियो ग्राम्शी ने रूसी क्रांति और पश्चिमी यूरोप की स्थितियों के बीच अंतर स्पष्ट किया। उन्होंने पाया कि पश्चिम में शासक वर्ग का वर्चस्व केवल राज्य की शक्ति पर नहीं, बल्कि एक सुदृढ़ नागरिक समाज और उसकी सांस्कृतिक संस्थाओं पर टिका है। इसलिए केवल सत्ता का तख्तापलट पर्याप्त नहीं है। क्रांतिकारियों को एक लंबी बौद्धिक लड़ाई लड़नी होगी ताकि वे जनमानस में अपनी वैचारिक हेजेमनी बना सकें और मौजूदा व्यवस्था की जड़ों को धीरे-धीरे कमजोर कर सकें।

160. (B) न्याय के निष्पक्ष सिद्धांतों को प्राप्त करने के लिए एक काल्पनिक विचार प्रयोग के रूप में कार्य करना।
जॉन रॉल्स की 'मूल स्थिति' एक ऐसा काल्पनिक मंच है जहाँ समाज के भविष्य के नियमों को तय करने के लिए लोग एकत्रित होते हैं। यहां 'अज्ञानता के पर्दे' का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि कोई भी अपनी व्यक्तिगत स्वार्थ या सामाजिक स्थिति के पक्ष में नियम न बना सके। इस निष्पक्ष स्थिति में लिए गए निर्णय ही वास्तविक न्याय को दर्शाते हैं। यह विचार प्रयोग यह समझने में मदद करता है कि एक आदर्श समाज की नींव किन सिद्धांतों पर होनी चाहिए।

161. (B) राष्ट्रीय स्व-हित और शक्ति की खोज।
कौटिल्य की विदेश नीति यथार्थवाद के सिद्धांतों पर आधारित है, जहाँ राज्य की सुरक्षा और समृद्धि ही राजा का सर्वोपरि लक्ष्य है। उनके अनुसार एक राजा को अन्य राष्ट्रों के साथ संबंध बनाते समय केवल इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उससे उसके अपने राज्य की शक्ति में वृद्धि हो। 'साम, दाम, दंड, भेद' जैसे साधनों का उपयोग इसी उद्देश्य के लिए किया जाता है। कौटिल्य का मानना था कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई स्थायी मित्र नहीं होता, केवल स्थायी हित होते हैं।

162. (A) केंद्रीकृत भारी औद्योगिकीकरण
महात्मा गांधी का सर्वोदय कार्यक्रम गांवों के उत्थान, कुटीर उद्योगों और आर्थिक स्वावलंबन पर केंद्रित था। वे बड़े शहरों और भारी मशीनों के केंद्रीकृत औद्योगिकीकरण को मानवीय गरिमा और पर्यावरण के लिए हानिकारक मानते थे। न्यासिता, ग्राम स्वराज और स्वदेशी उनके दर्शन के मूल आधार थे। गांधी जी का मानना था कि विकास का केंद्र गाँव होना चाहिए और तकनीक ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को रोजगार दे, न कि उन्हें बेरोजगार और पराश्रित बनाए। यह उनका मुख्य विचार था।

163. (C) शासकों की संख्या और उनके शासन का उद्देश्य।
अरस्तू ने संविधानों को वर्गीकृत करने के लिए दो वैज्ञानिक प्रश्न पूछे: शासन कितने लोगों के हाथ में है और शासन किसके हित के लिए किया जा रहा है? यदि शासन एक या बहुत से लोगों के हाथ में हो और उद्देश्य सार्वजनिक हित हो, तो वे शुद्ध रूप कहलाते हैं। यदि उद्देश्य केवल शासकों का निजी हित हो, तो वे विकृत रूप बन जाते हैं। यह वर्गीकरण राजनीति विज्ञान में तुलनात्मक अध्ययन की नींव रखता है और शासन प्रणालियों को समझने में सहायता करता है।

164. (A) केवल 1 और 2
जॉन लॉक के अनुसार प्रकृति ने संसाधन सभी को समान रूप से प्रदान किए हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति अपनी मेहनत को उन संसाधनों के साथ जोड़ता है, तो वह उसका निजी स्वामित्व प्राप्त कर लेता है। लॉक ने संपत्ति संचय पर कुछ सीमाएं भी लगाई थीं। उनके अनुसार व्यक्ति को केवल उतना ही संचय करना चाहिए जितना वह नष्ट होने से पहले उपयोग कर सके और दूसरों के लिए भी पर्याप्त संसाधन शेष रहें। यह 'लॉकियन प्रोविज़ो' के नाम से जाना जाता है और महत्वपूर्ण है।

NODIA

165. (C) सर्वहारा वर्ग के नेतृत्व में अर्ध-औपनिवेशिक देशों के लिए एक संक्रमणकालीन चरण।
माओ जेदोंग ने 'नई जनवाद' की अवधारणा चीन जैसी स्थितियों के लिए विकसित की थी। उनका मानना था कि समाजवाद में सीधे प्रवेश करने से पहले एक ऐसा चरण आवश्यक है जहाँ साम्राज्यवाद और सामंतवाद के विरुद्ध सभी देशभक्त वर्गों का गठबंधन हो। इस चरण का नेतृत्व सर्वहारा वर्ग और कम्युनिस्ट पार्टी के हाथों में होना चाहिए। यह उदार लोकतंत्र से भिन्न था क्योंकि इसका अंतिम लक्ष्य साम्यवाद की ओर बढ़ना था। यह चीन की विशिष्ट परिस्थितियों के अनुकूल एक रणनीतिक कदम था।

166. (B) टी.एच. ग्रीन
टी.एच. ग्रीन का यह प्रसिद्ध विचार राज्य की वैधता का आधार स्पष्ट करता है। उनके अनुसार राज्य केवल बल प्रयोग या कानून व्यवस्था के डर के कारण नहीं टिका है, बल्कि इसलिए बना हुआ है क्योंकि लोग इसे अपने सामूहिक कल्याण और अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक मानते हैं। जब नागरिकों की 'सामान्य इच्छा' राज्य का समर्थन करती है, तभी उसे वास्तविक अधिकार प्राप्त होता है। यह सिद्धांत राजनीतिक दायित्व को भय के बजाय नागरिकों की नैतिक सहमति और उत्तरदायित्व पर आधारित करता है।

167. (D) वी.डी. सावरकर
वी.डी. सावरकर को आधुनिक हिंदुत्व विचारधारा का मुख्य प्रणेता माना जाता है। उन्होंने अपनी पुस्तक 'हिंदुत्व' में इस अवधारणा को विस्तार से समझाया, जो हिंदू धर्म से अधिक व्यापक एक सांस्कृतिक और राजनीतिक पहचान है। सावरकर ने तर्क दिया कि हिंदुत्व का अर्थ है वे सभी लोग जो भारत को अपनी पितृभूमि और पुण्यभूमि दोनों मानते हैं। इस विचार का उद्देश्य बिखरे हुए हिंदू समाज को एक सूत्र में बांधना और उनमें राष्ट्रीय गौरव की भावना जागृत करना था। यह राष्ट्रवाद का आधार है।

168. (B) P-2, Q-1, R-4, S-3
प्राचीन ग्रीक दर्शन में 'पोलिस' का अर्थ एक आत्मनिर्भर राजनीतिक समुदाय या नगर-राज्य है। 'यूडेमोनिया' मानवीय सुख और उत्कर्ष की उस उच्चतम अवस्था को कहते हैं जो सद्गुणों के माध्यम से प्राप्त होती है। 'टेलोस' किसी भी वस्तु या संस्था के अंतिम लक्ष्य को दर्शाता है। 'फ्रोनेसिस' वह व्यावहारिक विवेक या बुद्धिमानी है जो सही निर्णय लेने में सहायक होती है। ये शब्द अरस्तू के राजनीतिक और नैतिक दर्शन को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण आधार और पारिभाषिक शब्दावली प्रदान करते हैं।

169. (C) यह सुनिश्चित करता है कि न्याय के सिद्धांत निष्पक्ष रूप से चुने जाएं।
जॉन रॉल्स के अनुसार अज्ञानता का पर्दा एक ऐसा नैतिक अवरोध है जो व्यक्तियों को उनकी निजी पहचान और हितों से परे सोचने को मजबूर करता है। जब किसी को यह नहीं पता होगा कि वह अमीर है या गरीब, शक्तिशाली है या कमजोर, तो वह स्वाभाविक रूप से ऐसे नियमों का चयन करेगा जो समाज के प्रत्येक सदस्य के लिए न्यायपूर्ण हों। यह विधि व्यक्तिगत पक्षपात को समाप्त करती है और न्याय के ऐसे सार्वभौमिक सिद्धांतों को जन्म देती है जो निष्पक्षता और समानता पर आधारित होते हैं।

170. (A) प्रत्येक सहयोगी और उसके अधिकारों का पूरे समुदाय के प्रति पूर्ण समर्पण।
रूसो के सामाजिक अनुबंध में व्यक्ति अपने अधिकारों को किसी राजा को नहीं, बल्कि पूरे समुदाय को सौंपता है। इस प्रक्रिया में वह अपनी प्राकृतिक स्वतंत्रता खो देता है, लेकिन एक नागरिक के रूप में 'नागरिक स्वतंत्रता' प्राप्त करता है। चूंकि प्रत्येक व्यक्ति समान रूप से स्वयं को समर्पित करता है, इसलिए कोई भी किसी दूसरे के अधीन नहीं होता। सभी नागरिक मिलकर 'सामान्य इच्छा' का निर्माण करते हैं, जो संप्रभु होती है और जिसका उद्देश्य हमेशा सार्वजनिक हित और सामूहिक भलाई होता है।

171. (D) यह धर्मपरायण लोगों की रक्षा करता है और धर्म तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखता है।
शांति पर्व में भीष्म ने युधिष्ठिर को उपदेश दिया कि दंड की शक्ति ही वह तत्व है जो संसार को मर्यादा में रखती है। बिना दंड के भय के शक्तिशाली लोग निर्बलों को पीड़ित करेंगे और सामाजिक संरचना छिन्न-भिन्न हो जाएगी। दंड केवल अपराधियों को सजा देने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह वह ईश्वरीय विधान है जो समाज में न्याय और सुरक्षा का वातावरण सुनिश्चित करता है। एक राजा के लिए दंड का उचित और धर्मसम्मत प्रयोग करना ही उसका सर्वोच्च कर्तव्य और धर्म माना गया है।

172. (B) स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व।
डॉ. अंबेडकर का मानना था कि सच्चा लोकतंत्र केवल एक राजनीतिक व्यवस्था नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। उन्होंने फ्रांसीसी क्रांति के इन तीन महान आदर्शों को भारतीय समाज के लिए अनिवार्य माना। उनके अनुसार स्वतंत्रता और समानता तब तक अधूरी हैं जब तक समाज में बंधुत्व या भाईचारे की भावना न हो। बंधुत्व ही वह तत्व है जो विभिन्न जातियों और वर्गों को एक राष्ट्र के रूप में जोड़ता है। अंबेडकर ने इन्हीं मूल्यों के आधार पर एक न्यायपूर्ण भारतीय समाज की कल्पना की थी।

173. (C) वाद, प्रतिवाद, संवाद
हेगेल की द्वंद्वात्मक पद्धति विकास की एक त्रिकोणीय प्रक्रिया है। इसमें पहले एक विचार या स्थिति (वाद) उत्पन्न होती है, फिर उसके आंतरिक विरोध से एक विपरीत स्थिति (प्रतिवाद) का जन्म होता है। इन दोनों के बीच संघर्ष के परिणामस्वरूप एक उच्च और अधिक तर्कसंगत स्थिति (संवाद) उभरती है। यह संवाद आगे चलकर फिर से एक नया वाद बन जाता है और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि परम सत्य या 'पूर्ण विचार' की प्राप्ति नहीं हो जाती। यह इतिहास की प्रगति का नियम है।

Click Here to Buy book on Amazon

174. (D) कार्ल मार्क्स
कार्ल मार्क्स के अनुसार समाज की संरचना दो मुख्य भागों में बंटी होती है। 'आधार' में उत्पादन की शक्तियां और आर्थिक संबंध शामिल होते हैं, जो समाज की असली बुनियाद हैं। 'अधिरचना' में कानून, राजनीति, धर्म और संस्कृति जैसे वैचारिक तत्व आते हैं जो आधार द्वारा निर्धारित होते हैं। मार्क्स का तर्क था कि यदि समाज में कोई वास्तविक परिवर्तन लाना है, तो उसके आर्थिक आधार को बदलना होगा। आधार में होने वाला बदलाव ही अधिरचना में क्रांति और परिवर्तन का मुख्य कारक बनता है।

175. (D) 1, 2, और 3
एम.एन. रॉय का जीवन विचारों के निरंतर विकास का उदाहरण है। उन्होंने एक उग्र राष्ट्रवादी के रूप में शुरुआत की। बाद में वे सोवियत संघ में कम्युनिस्ट आंदोलन के शीर्ष नेताओं में शामिल हुए। अपने अंतिम वर्षों में वे मार्क्सवाद की कट्टरता से विमुख हो गए और मौलिक मानवतावाद का दर्शन दिया। उनका यह अंतिम दर्शन व्यक्ति की स्वतंत्रता, तर्क और नैतिकता को केंद्र में रखता है जो सभी सामूहिक पहचानों से ऊपर है। रॉय ने दलविहीन लोकतंत्र की वकालत की ताकि वास्तविक जनशक्ति स्थापित हो सके।

176. (B) पॉलिटी
अरस्तू ने संवैधानिक तंत्र को एक शुद्ध और आदर्श शासन व्यवस्था माना है क्योंकि इसमें बहुमत का शासन पूरे समुदाय के सामान्य हित के लिए होता है। अन्य तीन—निरंकुश शासन, अल्पतंत्र और लोकतंत्र—स्वार्थी शासन माने गए हैं जहाँ शासक केवल अपने हितों की पूर्ति करते हैं। संवैधानिक तंत्र मध्यम वर्ग की प्रधानता वाला एक संतुलित संविधान है जो समाज में स्थिरता और न्याय सुनिश्चित करता है, इसलिए यह विकृत नहीं है। यह शासन व्यवस्था का सबसे टिकाऊ और संतुलित रूप माना जाता है।

177. (B) एक सभ्य समुदाय के स्वस्थ, वयस्क सदस्यों पर।
जे.एस. मिल का हानि सिद्धांत यह निर्धारित करता है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप केवल तभी जायज है जब वह दूसरों को नुकसान पहुँचाए। हालांकि मिल ने स्पष्ट किया कि यह सिद्धांत केवल उन लोगों पर लागू होता है जो अपनी तर्कशक्ति का उपयोग करने में सक्षम हैं। उन्होंने बच्चों और अविकसित समाजों को इस दायरे से बाहर रखा, क्योंकि उनका मानना था कि उन्हें मार्गदर्शन और नियंत्रण की आवश्यकता होती है। यह मिल के उदारवादी विचारों की एक विशिष्ट और कुछ हद तक विवादास्पद सीमा मानी जाती है।

178. (A) हॉब्स की अवस्था युद्ध की स्थिति है, जबकि लॉक की प्राकृतिक कानून द्वारा शासित और काफी हद तक शांतिपूर्ण है।
थॉमस हॉब्स ने प्राकृतिक अवस्था को एक भयावह युद्ध के रूप में देखा जहाँ मनुष्य का जीवन असुरक्षित था। इसके विपरीत, जॉन लॉक का मानना था कि मनुष्य स्वभाव से तर्कसंगत और शांतिप्रिय है। लॉक की प्राकृतिक अवस्था में लोग प्राकृतिक कानूनों का पालन करते थे और एक-दूसरे के अधिकारों का सम्मान करते थे। हॉब्स के लिए अनुबंध असुरक्षा से बचने की विवशता थी, जबकि लॉक के लिए यह प्राकृतिक अवस्था की असुविधाओं को दूर करने और अधिकारों को अधिक सुदृढ़ बनाने का एक तार्किक कदम था।

179. (A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
प्लेटो का मानना था कि राज्य के संरक्षक वर्ग के पास निजी संपत्ति और अपना परिवार नहीं होना चाहिए। उनका तर्क था कि संपत्ति के प्रति मोह और परिवार के प्रति पक्षपात शासकों को उनके सार्वजनिक कर्तव्यों से भटका सकता है। साम्यवाद की यह व्यवस्था शासकों को भ्रष्टाचार और स्वार्थ से बचाती है, जिससे वे पूरे राज्य को अपना परिवार मानकर निष्पक्षता से न्याय कर सकें। यह प्लेटो द्वारा एक पूर्णतः समर्पित और निस्वार्थ नेतृत्व तैयार करने का एक क्रांतिकारी और महत्वपूर्ण प्रयास था।

180. (D) अंतर-राज्य संबंधों का विश्लेषण करने और विदेश नीति तैयार करने के लिए एक ढांचा प्रदान करना।
कौटिल्य का मंडल सिद्धांत यह समझने में मदद करता है कि एक राजा को अपने पड़ोसियों और दूर स्थित राज्यों के साथ किस प्रकार के संबंध रखने चाहिए। इस सिद्धांत के अनुसार भौगोलिक स्थिति मित्रता या शत्रुता का मुख्य आधार होती है। यह 'विजिगीषु' राजा को यह पहचानने में सक्षम बनाता है कि उसका प्राकृतिक शत्रु कौन है और कौन सा राज्य उसका सहयोगी बन सकता है। यह कूटनीति का एक यथार्थवादी मॉडल है जो राज्य के सुरक्षा हितों और विस्तार की रणनीति को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है।

181. (C) पेशेवर क्रांतिकारियों की एक लघु, अनुशासित दल
लेनिन के अनुसार सर्वहारा वर्ग स्वयं में इतनी चेतना विकसित नहीं कर सकता कि वह पूंजीवाद को उखाड़ फेंके। इसके लिए उन्होंने एक 'अग्रगामी दल' का प्रस्ताव दिया। इस दल में वे लोग शामिल होते हैं जो मार्क्सवादी सिद्धांतों के गहरे ज्ञाता होते हैं और अपना पूरा जीवन क्रांति के लिए समर्पित कर देते हैं। यह एक गुप्त और केंद्रीय रूप से अनुशासित संगठन होता है जो आम जनता का मार्गदर्शन करता है और क्रांति के सही अवसर पर निर्णायक कार्रवाई सुनिश्चित करता है। यह दल ही क्रांति का नेतृत्व करता है।

182. (B) विकेंद्रीकृत, दलविहीन लोकतंत्र के आधार पर भारतीय राजनीति का पुनर्निर्माण।
जय प्रकाश नारायण ने दलीय राजनीति को भ्रष्टाचार और शक्ति के संघर्ष का मुख्य कारण माना। उन्होंने तर्क दिया कि वास्तविक लोकतंत्र तभी संभव है जब सत्ता ऊपर से थोपी न जाए, बल्कि गांवों और स्थानीय समुदायों से उत्पन्न हो। उनका 'दलविहीन लोकतंत्र' का विचार गांधीवादी आदर्शों से प्रेरित था जहाँ लोग दलीय भेदभाव से ऊपर उठकर ग्राम सभाओं के माध्यम से अपने मामलों का प्रबंधन स्वयं करते हैं। यह विचार भारतीय राजनीति में सत्ता के व्यापक विकेंद्रीकरण और सक्रिय जन-भागीदारी पर बल देता है।

NODIA

183. (D) समाज में अधीनस्थ या उत्पीड़ित सामाजिक समूह।
एंटोनियो ग्राम्शी ने 'सबल्टर्न' शब्द का उपयोग समाज के उन वर्गों के लिए किया जिन्हें राजनीतिक और आर्थिक शक्ति से वंचित रखा गया है। इसमें श्रमिक, किसान और अन्य उत्पीड़ित समूह शामिल हैं जिनकी अपनी कोई स्वतंत्र आवाज या संगठित नेतृत्व नहीं होता। ग्राम्शी के अनुसार शासक वर्ग का वर्चस्व इन समूहों को मानसिक रुप से भी अपना गुलाम बनाए रखता है। क्रांति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा इन समूहों में चेतना जागृत करना और उन्हें अपना स्वतंत्र राजनीतिक मंच प्रदान करना है ताकि वे संघर्ष कर सकें।

184. (A) एक लोकतांत्रिक सरकार जहाँ बहुमत अल्पसंख्यकों के अधिकारों और विचारों को दबा सकता है।
जे.एस. मिल ने चेतावनी दी थी कि लोकतंत्र में केवल राजा का डर नहीं होता, बल्कि समाज का 'बहुमत' भी निरंकुश हो सकता है। जब बहुमत अपने विचारों और जीवनशैली को अल्पसंख्यकों पर थोपने लगता है, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाती है। मिल का मानना था कि किसी भी व्यक्ति की विशिष्ट राय को केवल इसलिए नहीं दबाया जाना चाहिए क्योंकि वह बहुमत के खिलाफ है। लोकतंत्र की वास्तविक सफलता अल्पसंख्यकों के अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की पूर्ण सुरक्षा में ही निहित होती है।

185. (C) एक सिद्धांत कि धारित वस्तुओं में न्याय इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें कैसे प्राप्त और हस्तांतरित किया गया था।
रॉबर्ट नोजिक का हकदारी सिद्धांत वितरण के ऐतिहासिक पक्ष पर जोर देता है। उनके अनुसार यदि किसी व्यक्ति ने कोई संपत्ति न्यायपूर्ण तरीके से प्राप्त की है और उसे स्वेच्छा से हस्तांतरित किया गया है, तो वह व्यक्ति उस संपत्ति का वैध अधिकारी है। राज्य को सामाजिक समानता लाने के लिए इस संपत्ति को छीनने का कोई हक नहीं है। नोजिक के लिए न्याय का अर्थ किसी पूर्व-निर्धारित स्वरुप को प्राप्त करना नहीं, बल्कि व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकारों और अधिग्रहण की प्रक्रिया का पूर्ण सम्मान करना है।

186. (A) राज्य नैतिक जीवन की उच्चतम प्राप्ति है, जो सार्वभौमिक तर्क का अवतार है।
हेगेल के अनुसार राज्य केवल एक प्रशासनिक मशीनरी नहीं है, बल्कि यह वह सर्वोच्च संस्था है जहाँ मानवीय विवेक अपनी पूर्णता प्राप्त करता है। व्यक्ति राज्य का हिस्सा बनकर ही अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठता है और एक सार्वभौमिक उद्देश्य से जुड़ता है। हेगेल का मानना था कि राज्य में ही स्वतंत्रता और नैतिकता का वास्तविक समन्वय होता है। उनके लिए राज्य के प्रति आज्ञाकारिता ही व्यक्ति की तर्कसंगतता की उच्चतम अभिव्यक्ति है, क्योंकि राज्य परम सत्य का सांसारिक रुप माना गया है।

187. (D) कौटिल्य का मंडल सिद्धांत।
यह सिद्धांत कौटिल्य की कूटनीति का एक व्यावहारिक आधार है। मंडल सिद्धांत के अनुसार, एक राजा का पड़ोसी राज्य स्वाभाविक रूप से उसका शत्रु होता है, और उस शत्रु का पड़ोसी राज्य शत्रु का शत्रु होने के कारण मित्र बन जाता है। कौटिल्य ने राजाओं को सलाह दी कि वे अपने शत्रुओं को कमजोर करने के लिए उनके विरोधियों के साथ गठबंधन करें। यह यथार्थवादी दृष्टिकोण आज भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और रणनीतिक गठबंधनों को समझने में अत्यंत प्रासंगिक और महत्वपूर्ण माना जाता है।

188. (A) P-4, Q-1, R-2, S-3
अरस्तू की 'पॉलिटिक्स' प्राचीन राजनीतिक विज्ञान का आधार स्तंभ है। जॉन लॉक की 'टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट' ने उदारवादी लोकतंत्र और अधिकारों के सिद्धांत को जन्म दिया। कार्ल मार्क्स की 'दास कैपिटल' पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और शोषण का गहन विश्लेषण करती है। अरविंदो घोष की 'द लाइफ डिवाइन' मानव चेतना के आध्यात्मिक उत्थान और दैवीकरण का दर्शन प्रस्तुत करती है। ये चारों पुस्तकें अपने-अपने क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाली और राजनीति शास्त्र की अत्यंत सम्मानित रचनाएँ मानी जाती हैं।

189. (C) एक तर्कसंगत और नैतिक समाज के माध्यम से व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुनिश्चित करना।
एम.एन. रॉय का मौलिक मानवतावाद व्यक्ति को ब्रह्मांड का केंद्र मानता है। उनका मानना था कि समाज का उद्देश्य व्यक्ति का विकास होना चाहिए, न कि व्यक्ति को समाज की बलि चढ़ाना। रॉय के अनुसार जब मनुष्य तर्कसंगत सोच अपनाता है और अपनी आंतरिक नैतिकता को जगाता है, तभी वह वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है। यह दर्शन किसी भी प्रकार के धार्मिक अंधविश्वास या राजनीतिक तानाशाही का विरोध करता है और एक ऐसे विश्व की कल्पना करता है जहाँ प्रत्येक मानव गरिमापूर्ण और स्वतंत्र जीवन जी सके।

190. (D) जनता द्वारा समानता की या अभिजात वर्ग द्वारा श्रेष्ठता की आकांक्षा।
अरस्तू के अनुसार क्रांति का मूल कारण मनोवैज्ञानिक और सामाजिक होता है। जब समाज का एक बड़ा वर्ग यह महसूस करता है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है और उसे वह समानता नहीं मिल रही जिसका वह हकदार है, तो वह विद्रोह करता है। इसी तरह, जब धनी वर्ग यह महसूस करता है कि उसे अपनी श्रेष्ठता के अनुरुप शक्ति नहीं मिल रही, तो वह भी व्यवस्था बदलने का प्रयास करता है। न्याय की यह धारणा और असमानता का बोध ही राजनीतिक अस्थिरता और क्रांतियों का मुख्य स्रोत माना गया है।

191. (C) केवल 1 और 3
रूसो की सामान्य इच्छा सदैव सार्वजनिक कल्याण की ओर अग्रसर होती है और इसे कभी गलत नहीं माना जा सकता क्योंकि यह सामूहिक नैतिकता का प्रतीक है। रूसो का यह भी मानना था कि संप्रभुता को किसी प्रतिनिधि को सौंपा नहीं जा सकता, इसलिए सामान्य इच्छा का प्रतिनिधित्व संभव नहीं है; इसे नागरिकों को स्वयं प्रत्यक्ष रुप से व्यक्त करना चाहिए। यह इच्छा व्यक्तिगत स्वार्थों को त्यागकर समाज के सामूहिक हित को प्राथमिकता देती है, जो एक न्यायपूर्ण और लोकतांत्रिक राज्य का अनिवार्य आधार माना गया है।

Downloaded from www.pdf.tube

192. (B) मित्र
कौटिल्य ने विदेश नीति के छह लक्षणों का वर्णन किया है, जिनमें संधि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय और द्वैधीभाव शामिल हैं। 'मित्र' सप्तांग सिद्धांत का एक अंग है, लेकिन वह छह लक्षणों वाली नीति का सीधा हिस्सा नहीं है। इस नीति का उद्देश्य यह तय करना है कि किसी विशेष परिस्थिति में राजा को शत्रु के साथ समझौता करना चाहिए, युद्ध करना चाहिए या केवल तैयारी करनी चाहिए। यह कूटनीति का एक अत्यंत लचीला और यथार्थवादी ढांचा प्रदान करता है जो राज्य के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

193. (B) परिणामवाद
उपयोगितावाद एक परिणामवादी दर्शन है क्योंकि यह किसी भी कार्य की नैतिकता का निर्धारण उसके परिणामों के आधार पर करता है। बेंथम के अनुसार यदि किसी कार्य का परिणाम सुख में वृद्धि और दुख में कमी है, तो वह कार्य सही है। यहाँ नियत या कर्तव्य के बजाय 'अंतिम सुख' को महत्व दिया जाता है। यह विचारधारा मानती है कि नीतियों का मूल्यांकन इस आधार पर किया जाना चाहिए कि वे समाज के अधिकतम व्यक्तियों के लिए कितना लाभ या सुख उत्पन्न कर रही हैं। यह व्यावहारिक दृष्टिकोण पर आधारित है।

194. (A) विधि के शासन और एक सुदृढ़ मध्यम वर्ग द्वारा शासित एक संवैधानिक पॉलिटी।
प्लेटो ने एक काल्पनिक और पूर्णतः आदर्श राज्य की कल्पना की थी जहाँ दार्शनिक राजा का विवेक कानून से ऊपर था। इसके विपरीत अरस्तू ने अधिक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए 'संवैधानिक तंत्र' का समर्थन किया। उनके अनुसार एक स्थिर राज्य वह है जहाँ लिखित कानून का शासन हो और जहाँ मध्यम वर्ग इतना मजबूत हो कि वह धनी और निर्धन वर्गों के बीच संतुलन बनाए रख सके। अरस्तू के लिए पूर्ण आदर्श के बजाय 'सर्वोत्तम संभव' और 'टिकाऊ' व्यवस्था अधिक महत्वपूर्ण और समाज के लिए हितकारी थी।

195. (C) धनी व्यक्तियों को अपनी अतिरिक्त संपत्ति समाज के लिए न्यास के रूप में रखनी चाहिए।
गांधी जी का न्यासिता का सिद्धांत वर्ग संघर्ष का एक अहिंसक विकल्प था। उनका मानना था कि ईश्वर ने जो भी संपत्ति दी है, वह पूरी मानवता के लिए है। धनी व्यक्तियों को स्वयं को उस संपत्ति का एकमात्र मालिक नहीं समझना चाहिए, बल्कि समाज के एक न्यासी के रूप में उसका प्रबंधन करना चाहिए। वे अपनी गरिमापूर्ण आजीविका के लिए आवश्यक हिस्सा रख सकते हैं, लेकिन शेष धन का उपयोग उन्हें गरीबों के कल्याण के लिए करना चाहिए। यह विचार स्वैच्छिक त्याग और नैतिकता पर आधारित आर्थिक समानता चाहता था।

196. (D) अरस्तू
अरस्तू का यह प्रसिद्ध कथन मनुष्य की सामाजिक और राजनीतिक प्रकृति को उजागर करता है। उनके अनुसार मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति और सद्गुणी जीवन जीने के लिए स्वाभाविक रूप से समाज और राज्य की ओर आकर्षित होता है। जो व्यक्ति समाज से बाहर रह सकता है, वह या तो पशु है या ईश्वर। राज्य केवल सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि मानव की पूर्णता के लिए अनिवार्य है। राजनीति में भाग लेना और सामूहिक निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा बनना ही मनुष्य की विशिष्ट विशेषता और उसका गौरव माना गया है।

197. (C) रॉबर्ट नोज़िक
रॉबर्ट नोज़िक एक प्रखर उदारतावादी विचारक थे जिन्होंने व्यक्तिगत आत्म-स्वामित्व पर बल दिया। उनका तर्क था कि चूंकि व्यक्ति अपने श्रम और शरीर का स्वामी है, इसलिए उसकी मेहनत से अर्जित धन पर केवल उसका अधिकार है। जब राज्य कर लगाता है, तो वह वास्तव में व्यक्ति के काम के घंटों के फल को जबरन छीन लेता है, जो 'जबरन श्रम' या दासता के समान है। नोजिक के अनुसार केवल सुरक्षा प्रदान करने के लिए लिया गया न्यूनतम कर ही न्यायोचित हो सकता है, इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी कर अनैतिक है।

198. (A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
कार्ल मार्क्स ने अपने सिद्धांतों को 'वैज्ञानिक समाजवाद' कहा क्योंकि वे केवल नैतिक आधार पर समाजवाद की कल्पना नहीं कर रहे थे। उन्होंने इतिहास का भौतिकवादी विश्लेषण किया और पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली के भीतर अंतर्निहित अंतर्विरोधों को वैज्ञानिक रूप से उजागर किया। मार्क्स ने पुराने 'काल्पनिक समाजवादियों' की आलोचना की क्योंकि उनके पास क्रांति की कोई ठोस कार्ययोजना या ऐतिहासिक आधार नहीं था। मार्क्स का मानना था कि पूंजीवाद का पतन और समाजवाद का आगमन ऐतिहासिक विकास का एक अनिवार्य परिणाम है।

199. (D) वी.आई. लेनिन
लेनिन के अनुसार राज्य कोई प्राकृतिक संस्था नहीं है, बल्कि यह समाज के भीतर वर्गों के बीच होने वाले निरंतर और अपूरणीय संघर्ष का परिणाम है। जब समाज शोषक और शोषित वर्गों में बंट जाता है और उनके हितों के बीच समझौता असंभव हो जाता है, तब शासक वर्ग अपने हितों की रक्षा के लिए राज्य तंत्र का निर्माण करता है। राज्य का अस्तित्व ही इस बात का प्रमाण है कि समाज में गहरे वर्ग अंतर्विरोध मौजूद हैं जिन्हें बिना क्रांति के हल नहीं किया जा सकता। राज्य दमन का एक संगठित उपकरण होता है।

200. (A) व्यक्तिगत नैतिक आचरण और आत्म-नियंत्रण।
शांति पर्व में भीष्म ने युधिष्ठिर को उन पांच आंतरिक गुणों के बारे में बताया जो एक राजा के चरित्र के लिए अनिवार्य हैं। इनमें क्रोध पर विजय, सत्य का पालन, क्षमा, दान और पवित्रता शामिल हैं। यह आधुनिक विदेश नीति के सिद्धांतों से पूरी तरह अलग है। प्राचीन संदर्भ में यह राजा के आत्म-अनुशासन और नैतिक बल पर केंद्रित था, क्योंकि माना जाता था कि एक संयमित और सदाचारी राजा ही अपनी प्रजा का सही मार्गदर्शन कर सकता है और राज्य में धर्म की स्थापना कर सकता है।

201. (A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
टी.एच. ग्रीन के अनुसार नकारात्मक स्वतंत्रता केवल बंधनों का अभाव है, जो पर्याप्त नहीं है। वास्तविक स्वतंत्रता 'सकारात्मक' है, जिसका अर्थ है अपनी उच्च क्षमताओं को साकार करने की

NODIA

शक्ति। यदि कोई व्यक्ति अज्ञानता या गरीबी के कारण अपना विकास नहीं कर पा रहा है, तो वह वास्तव में स्वतंत्र नहीं है। राज्य का दायित्व है कि वह इन बाधाओं को हटाकर ऐसी परिस्थितियाँ पैदा करे जहाँ नागरिक नैतिक और बौद्धिक रूप से समृद्ध हो सकें। यह विचार उदारवाद को सामाजिक कल्याण के व्यापक उद्देश्यों से जोड़ता है।

202. (A) मार्क्स और एंगेल्स
यह प्रसिद्ध नारा 'कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो' के समापन पर दिया गया था। मार्क्स और एंगेल्स का मानना था कि श्रमिकों की कोई राष्ट्रीयता नहीं होती क्योंकि पूरी दुनिया में पूंजीवादी शोषण का स्वरुप एक जैसा है। उन्होंने दुनिया भर के मजदूरों से अपील की कि वे अपने आपसी मतभेद भुलाकर एक अंतर्राष्ट्रीय शक्ति के रूप में संगठित हों। उनका तर्क था कि मजदूरों के पास खोने के लिए केवल अपनी जंजीरें हैं, लेकिन जीतने के लिए पूरी दुनिया है। यह नारा वैश्विक सर्वहारा एकजुटता का प्रतीक बन गया।

203. (D) एक सिद्धांत जो उन सामाजिक संदर्भों पर बल देता है जो पहचान को आकार देते हैं।
समुदायवाद एक ऐसी विचारधारा है जो उदारवादी व्यक्तिवाद के विरुद्ध तर्क देती है। इसके अनुसार व्यक्ति कोई स्वतंत्र परमाणु नहीं है, बल्कि वह अपने परिवार, संस्कृति और समुदाय के साझा इतिहास और मूल्यों से निर्मित होता है। समुदायवादियों का मानना है कि अधिकारों और न्याय की चर्चा सामाजिक संबंधों और साझा भलाई से अलग होकर नहीं की जा सकती। हमारी पहचान और उद्देश्य हमारे समुदाय के भीतर ही सार्थक होते हैं, इसलिए समुदाय को राजनीतिक चिंतन का केंद्र होना चाहिए। यह व्यक्ति की सामाजिक प्रकृति पर बल देता है।

204. (B) अर्थशास्त्र के विज्ञान को
कौटिल्य के अनुसार 'वार्ता' राज्य की अर्थव्यवस्था का आधार है जिसमें कृषि, पशुपालन और व्यापार शामिल हैं। एक राजा के लिए वार्ता का ज्ञान होना अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी से राज्य का कोष भरता है और प्रजा की समृद्धि सुनिश्चित होती है। कौटिल्य का मानना था कि आर्थिक स्थिरता ही सैन्य शक्ति और राज्य की सुरक्षा की नींव है। जिस राज्य की आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ नहीं होती, वह बाहरी आक्रमणों और आंतरिक विद्रोहों के प्रति संवेदनशील हो जाता है। अतः अर्थव्यवस्था शासन का मूल आधार है।

205. (C) शक्ति का अर्जन और संरक्षण।
मैकियावेली के अनुसार राजनीति का मुख्य उद्देश्य सत्ता को प्राप्त करना और उसे किसी भी कीमत पर बनाए रखना है। उन्होंने शासक को सलाह दी कि वह नैतिकता के बजाय यथार्थवाद पर ध्यान दे। राजा का सर्वोच्च कर्तव्य अपने राज्य की सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करना है। यदि इसके लिए उसे क्रूरता या धोखे का सहारा लेना पड़े, तो उसे संकोच नहीं करना चाहिए। मैकियावेली के लिए 'परिणाम' ही 'साधनों' को उचित ठहराते हैं, और एक सफल शासक वही है जो सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत रखता है।

206. (D) थॉमस हॉब्स
थॉमस हॉब्स ने अपनी पुस्तक 'लेविआथन' में प्राकृतिक अवस्था का अत्यंत अंधकारमय चित्रण किया है। उनके अनुसार एक केंद्रीय सत्ता या सरकार के अभाव में मनुष्य निरंतर भय और आपसी युद्ध की स्थिति में रहता है जहाँ हर कोई दूसरे का शत्रु है। वहां उद्योग, कला और समाज के लिए कोई स्थान नहीं है क्योंकि किसी का जीवन सुरक्षित नहीं है। इसी निरंतर असुरक्षा के कारण मानव जीवन अत्यंत दयनीय और अल्प होता है। इसी भयावह स्थिति से मुक्ति के लिए लोग सामाजिक अनुबंध करते हैं और संप्रभु की स्थापना करते हैं।

207. (A) संयुक्त निर्वाचक मंडल बहुमत के अधीन प्रतिनिधियों को चुन सकते हैं।
डॉ. अंबेडकर का मानना था कि पूना पैक्ट के माध्यम से दलितों ने पृथक निर्वाचक मंडल का अपना वास्तविक अधिकार खो दिया। यद्यपि सीटों का आरक्षण बढ़ गया था, लेकिन मतदान संयुक्त होने के कारण दलित प्रतिनिधियों को चुनने में सवर्ण हिंदुओं की भूमिका निर्णायक हो गई। अंबेडकर को डर था कि ऐसे प्रतिनिधि दलितों के हितों के प्रति पूरी तरह वफादार नहीं रहेंगे क्योंकि उन्हें चुनाव जीतने के लिए सवर्ण बहुमत का समर्थन प्राप्त करना होगा। उन्होंने इसे दलितों के राजनीतिक सशक्तिकरण के साथ एक बड़ा समझौता माना।

208. (A) केवल 1 और 2
हेगेल के अनुसार विश्व इतिहास केवल घटनाओं का संग्रह नहीं है, बल्कि यह मानवीय चेतना और स्वतंत्रता के क्रमिक विकास की एक तर्कसंगत यात्रा है। इतिहास की यह प्रक्रिया द्वंद्वात्मक है जो वाद, प्रतिवाद और संवाद के माध्यम से आगे बढ़ती है। हेगेल का मानना था कि राज्य इस विकास का उच्चतम शिखर है जहाँ स्वतंत्रता अपने पूर्ण रूप में संस्थागत हो जाती है। उनके लिए इतिहास का स्वरूप अराजक नहीं, बल्कि एक निश्चित लक्ष्य और तर्कसंगतता की ओर निर्देशित होता है। यह विकास की एक अनिवार्य प्रक्रिया है।

209. (B) माओ
माओ जेदोंग ने 'सांस्कृतिक क्रांति' का आह्वान यह सुनिश्चित करने के लिए किया था कि चीन में साम्यवादी विचारधारा शुद्ध बनी रहे और समाज में पूंजीवादी मानसिकता का पुनरुत्थान न हो। उनका मानना था कि केवल आर्थिक बदलाव पर्याप्त नहीं हैं; लोगों की सोच और संस्कृति को भी पूरी तरह बदलना होगा। इस आंदोलन के दौरान पुराने रीति-रिवाजों और बुर्जुआ मूल्यों पर कड़ा प्रहार किया गया। माओ का लक्ष्य एक ऐसी निरंतर क्रांति था जो समाज में वर्गहीनता और साम्यवादी आदर्शों को गहराई से स्थापित कर सके और व्यवस्था को सुदृढ़ रखे।

210. (A) भेद का सिद्धांत
जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत का यह एक महत्वपूर्ण भाग है जो आर्थिक असमानताओं को एक विशेष शर्त के साथ स्वीकार करता है। इसके अनुसार समाज में संसाधनों का वितरण केवल तभी असमान हो सकता है जब वह असमानता समाज के सबसे गरीब और पिछड़े व्यक्तियों को अधिकतम लाभ पहुँचा रही हो। यह सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि एक न्यायपूर्ण

Click Here to Buy book on Amazon

समाज को अपने सबसे कमजोर सदस्यों की स्थिति सुधारने को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। यह कल्याणकारी नीतियों के लिए एक सशक्त और तर्कसंगत नैतिक आधार प्रदान करता है।

211. (C) पदार्थ से अतिमानस तक आध्यात्मिक विकास का एक सिद्धांत।
अरविंदो घोष की 'द लाइफ डिवाइन' उनके दार्शनिक चिंतन का मुख्य ग्रंथ है। इसमें उन्होंने ब्रह्मांडीय विकास की व्याख्या की है, जिसके अनुसार चेतना पदार्थ से प्राण, फिर मन और अंततः 'अतिमानस' की ओर बढ़ रही है। उनका मानना था कि मनुष्य विकास का अंतिम चरण नहीं है, बल्कि वह एक उच्च दैवीय चेतना की ओर संक्रमण कर रहा है। यह पुस्तक न केवल व्यक्तिगत आध्यात्मिक साधना की बात करती है, बल्कि पूरी मानवता के सामूहिक रूपांतरण और पृथ्वी पर दिव्य जीवन की संभावना को स्पष्ट रूप से रेखांकित करती है।

212. (D) P-2, Q-1, R-3
थॉमस हॉब्स ने एक निरंकुश और असीमित संप्रभुता का समर्थन किया जो कानून से ऊपर है। जॉन लॉक ने सीमित और उत्तरदायी संप्रभुता की वकालत की जो जनता के प्राकृतिक अधिकारों से बंधी हुई है। ज्यां-जैक रूसो ने लोकप्रिय संप्रभुता का विचार दिया जो 'सामान्य इच्छा' में निहित है और जिसे प्रतिनिधियों को सौंपा नहीं जा सकता। ये तीनों दृष्टिकोण राजनीतिक सत्ता के स्रोत और उसकी सीमाओं के बारे में अलग-अलग धारणाएं प्रस्तुत करते हैं, जो आधुनिक राज्य के विकास और लोकतांत्रिक विमर्श को समझने में अत्यंत सहायक हैं।

213. (C) कार्ल मार्क्स
कार्ल मार्क्स का यह प्रसिद्ध कथन उनके दर्शन की क्रांतिकारी प्रकृति को दर्शाता है। वे केवल अकादमिक चर्चाओं के पक्ष में नहीं थे। मार्क्स का मानना था कि दर्शन का वास्तविक उद्देश्य समाज में व्याप्त शोषण और अन्याय को समझना और उसे सक्रिय रूप से बदलना होना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि विचारकों को केवल दुनिया का विश्लेषण नहीं करना चाहिए, बल्कि सर्वहारा वर्ग को संगठित करके पूंजीवाद को उखाड़ फेंकने और एक न्यायपूर्ण साम्यवादी समाज बनाने के लिए कार्य करना चाहिए। यह सिद्धांत और व्यवहार के एकीकरण का संदेश है।

214. (B) यदि निष्क्रिय प्रतिरोध विफल हो जाए तो अरविंदो ने हिंसा के उपयोग को एक वैध विकल्प के रूप में स्वीकार किया था।
अरविंदो घोष का निष्क्रिय प्रतिरोध एक राजनीतिक रणनीति थी जिसमें बहिष्कार और असहयोग शामिल था, लेकिन उनके लिए अहिंसा कोई पूर्ण नैतिक सिद्धांत नहीं था जैसा कि गांधी जी के लिए था। अरविंदो का मानना था कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए यदि आवश्यक हो तो सशस्त्र संघर्ष भी किया जा सकता है। इसके विपरीत, गांधी जी का सत्याग्रह पूर्णतः अहिंसा और प्रेम पर आधारित था, जहाँ वे शत्रु के हृदय परिवर्तन की बात करते थे और किसी भी स्थिति में हिंसा को वर्जित मानते थे। यह दोनों के दृष्टिकोणों में मूल अंतर था।

215. (D) यह पूर्ण और अविभाज्य है।
थॉमस हॉब्स के अनुसार संप्रभुता को न तो सीमित किया जा सकता है और न ही साझा किया जा सकता है। यदि संप्रभु की शक्तियों को विभाजित किया जाए, तो विभिन्न केंद्रों के बीच संघर्ष की संभावना बढ़ जाती है, जिससे समाज पुनः अराजकता की स्थिति में पहुँच सकता है। लेविआथन को सभी शक्तियों—कानूनी, विधायी, न्यायिक और सैन्य—का एकमात्र स्रोत होना चाहिए। हॉब्स का मानना था कि केवल एक अविभाज्य और सर्वोच्च सत्ता ही प्रजा की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती है और समाज में स्थायी शांति बनाए रख सकती है। यह पूर्ण संप्रभुता का विचार है।

216. (A) राज्य के तत्वों या अंगों को।
कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 'प्रकृति' शब्द का उपयोग राज्य को बनाने वाले सात मूलभूत अंगों के लिए किया गया है। सप्तांग सिद्धांत के अनुसार ये सात प्रकृतियां—स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र—मिलकर एक संपूर्ण राज्य का निर्माण करती हैं। प्रत्येक प्रकृति की अपनी विशिष्ट विशेषता और महत्व है। कौटिल्य का मानना था कि राज्य की शक्ति और समृद्धि इन सात प्रकृतियों की गुणवत्ता और उनके बीच के आपसी सामंजस्य पर निर्भर करती है। यह प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में राज्य की संरचना का एक संगठित विश्लेषण है।

217. (C) पॉलिटि एक मिश्रित संविधान है जो धनी और निर्धन के हितों को संतुलित करता है।
अरस्तू के अनुसार 'लोकतंत्र' केवल गरीबों का शासन है जो अमीरों का शोषण कर सकता है, जबकि 'अल्पतंत्र' केवल अमीरों का शासन है जो गरीबों को दबाता है। 'संवैधानिक तंत्र' इन दोनों का एक आदर्श मिश्रण है जिसमें मध्यम वर्ग की प्रधानता होती है। यह व्यवस्था कानून के शासन पर आधारित होती है और समाज के किसी भी एक वर्ग को निरंकुश होने से रोकती है। मध्यम वर्ग स्थिरता का स्रोत है क्योंकि वह न तो बहुत लालची होता है और न ही बहुत ईर्ष्यालु, जो इसे सर्वोत्तम और सर्वाधिक व्यावहारिक शासन व्यवस्था बनाता है।

218. (A) रॉबर्ट नोजिक
रॉबर्ट नोजिक ने अपनी इस कालजयी कृति में जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांतों की कड़ी आलोचना की। उन्होंने तर्क दिया कि व्यक्तिगत अधिकारों का सम्मान करने वाला एकमात्र राज्य 'न्यूनतम राज्य' है। नोजिक के अनुसार किसी भी प्रकार का पुनर्वितरणकारी न्याय अनैतिक है क्योंकि वह व्यक्तियों की मेहनत से अर्जित संपत्ति को उनकी सहमति के बिना छीन लेता है। यह पुस्तक समकालीन उदारतावादी राजनीति विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक मानी जाती है, जिसने स्वतंत्र बाजार और सीमित सरकार के पक्ष में सशक्त दलीलें पेश कीं।

219. (A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
मैकियावेली के अनुसार मानव स्वभाव मूलतः स्वार्थी और अविश्वसनीय है। लोग प्रेम केवल तब तक करते हैं जब तक उनका हित सधता है, लेकिन जैसे ही संकट आता है, वे बदल जाते हैं। इसके विपरीत, भय एक ऐसा आवेग है जो दंड की संभावना के कारण कभी विफल नहीं होता। इसलिए एक

Downloaded from www.pdf.tube

राजकुमार के लिए प्रजा का भय प्राप्त करना अधिक सुरक्षित है ताकि वह अपनी सत्ता को स्थिरता प्रदान कर सके। हालांकि उन्होंने चेतावनी दी कि राजा को डर पैदा करना चाहिए, लेकिन घृणा का पात्र बनने से बचना चाहिए ताकि प्रजा विद्रोह न करे।

220. (B) आधुनिक, औद्योगिक, भौतिकवादी सभ्यता की मौलिक आलोचना करना।
'हिंद स्वराज' में महात्मा गांधी ने तर्क दिया कि भारत की असली समस्या केवल अंग्रेज नहीं, बल्कि वह पश्चिमी सभ्यता है जिसे वे अपने साथ लाए हैं। उन्होंने इस सभ्यता को 'अधर्मी' माना क्योंकि यह शरीर के सुख को आत्मा के ऊपर रखती है। गांधी जी के अनुसार भारत का वास्तविक उद्धार अपनी प्राचीन संस्कृति की ओर लौटने और मशीनी युग के लालच को त्यागने में है। स्वराज का अर्थ केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं, बल्कि अपनी स्वदेशी परंपराओं के अनुसार जीवन जीना और स्वयं पर पूर्ण आत्म-नियंत्रण करना है।

221. (C) किसी विशिष्ट हठधर्मिता या आस्तिक विश्वास का पालन करना।
सावरकर के अनुसार हिंदुत्व एक सांस्कृतिक और राष्ट्रीय पहचान है, जो किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत धार्मिक आस्था या पूजा पद्धति पर निर्भर नहीं करती। एक व्यक्ति नास्तिक होकर भी हिंदू हो सकता है, बशर्ते वह भारत को अपनी पितृभूमि और पुण्यभूमि मानता हो और साझा हिंदू संस्कृति व इतिहास से जुड़ाव महसूस करता हो। सावरकर ने हिंदुत्व को एक 'हिंदू राष्ट्र' के निर्माण के आधार के रूप में देखा जहाँ साझा जातीयता और भौगोलिक निष्ठा किसी भी धार्मिक हठधर्मिता से अधिक महत्वपूर्ण मानी गई है। यह समग्र एकता का विचार है।

222. (D) साम्राज्यवाद एकाधिकार पूंजीवाद के लिए एक आर्थिक आवश्यकता है।
लेनिन के अनुसार जब पूंजीवाद अपने उच्चतम चरण में पहुँचता है, तो विशाल बैंक और उद्योग आपस में मिलकर 'वित्तीय पूंजी' का निर्माण करते हैं। घरेलू बाजार में अधिक निवेश की संभावना न होने के कारण यह पूंजी नए क्षेत्रों की तलाश करती है। इससे दुनिया के संसाधनों और बाजारों पर नियंत्रण के लिए साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा शुरू होती है। लेनिन का मानना था कि साम्राज्यवाद अनिवार्य रूप से युद्धों और शोषण को जन्म देता है और यह पूंजीवाद के अंत की शुरुआत का संकेत है। यह वैश्विक स्तर पर पूंजीवादी प्रसार का हिंसक रूप है।

223. (A) जॉन रॉल्स
जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत में 'मूल स्थिति' एक ऐसा काल्पनिक प्रारंभिक बिंदु है जहाँ न्याय के सिद्धांतों का चयन किया जाता है। यहाँ 'अज्ञानता का पर्दा' यह सुनिश्चित करता है कि निर्णय लेने वाले व्यक्ति अपनी वास्तविक सामाजिक स्थिति, संपत्ति या क्षमताओं से अनभिज्ञ हों। इस निष्पक्षता के कारण वे ऐसे नियमों का चुनाव करते हैं जो समाज के सबसे कमजोर वर्ग की रक्षा करें। यह अवधारणा न्याय को निष्पक्षता के रूप में स्थापित करती है और व्यक्तिगत पक्षपात को राजनीतिक चिंतन से बाहर करने का एक दार्शनिक प्रयास करती है।

224. (C) केवल 1 और 3
जे.एस. मिल व्यक्तिगत स्वतंत्रता के कट्टर समर्थक थे और उन्होंने अभिव्यक्ति की आजादी को मानव प्रगति के लिए अनिवार्य माना। उन्होंने तर्क दिया कि राज्य को व्यक्ति के 'स्व-विषयक' कार्यों में बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मिल के अनुसार स्वतंत्रता केवल इसलिए मूल्यवान नहीं है कि वह एक अधिकार है, बल्कि इसलिए कि वह समाज में नई प्रतिभाओं और विचारों को उभरने का अवसर देती है जिससे पूरी मानवता का हित होता है। वे बहुमत की निरंकुशता से व्यक्तिगत स्वायत्तता की रक्षा करना चाहते थे ताकि समाज का उत्कर्ष हो सके।

NODIA

225. (B) मार्क्सवादी ऐतिहासिक भौतिकवाद
मार्क्सवादी दर्शन का यह आधारभूत सिद्धांत हेगेल के आदर्शवाद को चुनौती देता है। मार्क्स के अनुसार हमारे विचार, चेतना और कानून हवा में पैदा नहीं होते, बल्कि वे हमारे भौतिक जीवन की स्थितियों और उत्पादन के आर्थिक संबंधों से उत्पन्न होते हैं। जैसे-जैसे मनुष्य की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के तरीके बदलते हैं, वैसे-वैसे उसकी सोच और सामाजिक संस्थाएं भी बदलती हैं। संक्षेप में, समाज का आर्थिक ढांचा ही उसकी राजनीतिक और वैचारिक अधिरचना को निर्धारित करने वाला प्राथमिक कारक है। यह ऐतिहासिक परिवर्तन की भौतिकवादी व्याख्या है।

226. (A) अपने जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के पारस्परिक संरक्षण के लिए।
जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में यद्यपि लोग स्वतंत्र थे, लेकिन वहां अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में निष्पक्ष न्याय का अभाव था। लोग निरंतर असुरक्षा महसूस करते थे क्योंकि वहां कोई सामान्य सत्ता नहीं थी जो विवादों का समाधान कर सके। इसी कारण उन्होंने आपसी सहमति से एक राजनीतिक समाज का निर्माण किया। लॉक का मानना था कि सरकार का एकमात्र वैध उद्देश्य इन तीन मौलिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यदि सरकार इसमें विफल होती है, तो जनता के पास उसे बदलने और नई व्यवस्था बनाने का अधिकार है।

227. (A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
रूसो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के प्रस्तावक थे और वे प्रतिनिधि शासन को वास्तविक स्वतंत्रता का हनन मानते थे। उनके अनुसार संप्रभुता 'सामान्य इच्छा' में निहित है, जो समाज के सामूहिक हित का प्रतिनिधित्व करती है। चूंकि इच्छा को किसी दूसरे को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता, इसलिए संप्रभुता का भी प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता। जैसे ही कोई समाज प्रतिनिधियों को कानून बनाने की शक्ति सौंप देता है, वह स्वतंत्र नहीं रह जाता। रूसो के लिए नागरिकों की प्रत्यक्ष भागीदारी ही सच्ची संप्रभुता और राजनीतिक स्वतंत्रता का सार है।

228. (D) हेजेमनी
एंटोनियो ग्राम्शी की वर्चस्व की अवधारणा यह बताती है कि कैसे एक शासक वर्ग हिंसा के बिना भी समाज पर नियंत्रण बनाए रखता है। यह नियंत्रण सांस्कृतिक और वैचारिक

माध्यमों से प्राप्त किया जाता है, जहाँ समाज की संस्थाएं—जैसे स्कूल और मीडिया—शासक वर्ग के मूल्यों को 'सामान्य बोध' के रूप में प्रचारित करती हैं। जब आम जनता इन मूल्यों को स्वतः स्वीकार कर लेती है, तो शासक वर्ग को अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए बल प्रयोग की आवश्यकता नहीं रह जाती। यह वैचारिक नेतृत्व के माध्यम से स्थापित किया गया एक गहरा सामाजिक प्रभुत्व है।

229. (C) जे.एस. मिल
जे.एस. मिल ने इस प्रभावशाली पुस्तक की रचना की थी। इसमें उन्होंने तर्क दिया कि महिलाओं को पुरुषों के अधीन रखना प्राकृतिक नहीं, बल्कि केवल प्राचीन प्रथा और शक्ति का परिणाम है। मिल ने महिलाओं के लिए मतदान के अधिकार, शिक्षा और संपत्ति के समान अधिकारों की पुरजोर वकालत की। उनका मानना था कि महिलाओं की मुक्ति न केवल उनके लिए न्यायपूर्ण है, बल्कि यह पूरी मानवता की प्रगति और सुख में वृद्धि करने वाली एक अनिवार्य आवश्यकता है। यह कृति नारीवादी विमर्श और सामाजिक समानता के क्षेत्र में मील का पत्थर मानी जाती है।

230. (B) राज्य की एक प्राकृतिक और आवश्यक इकाई, जो प्रजनन और दैनिक आवश्यकताओं के लिए अनिवार्य है।
अरस्तू ने राज्य के विकास को एक क्रमिक प्रक्रिया माना जिसमें परिवार प्राथमिक इकाई है। परिवार मनुष्य की जैविक और बुनियादी जरूरतों को पूरा करता है। कई परिवारों के मिलने से गाँव बनता है और अंततः कई गाँवों के मिलने से 'राज्य' का जन्म होता है। अरस्तू ने प्लेटो के साम्यवाद का विरोध करते हुए परिवार की रक्षा की, क्योंकि वे इसे स्नेह और सामाजिक नैतिकता का मूल स्रोत मानते थे। उनके अनुसार राज्य का अस्तित्व परिवार जैसी प्राकृतिक संस्थाओं को समाप्त करने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें पूर्णता और श्रेष्ठ जीवन प्रदान करने के लिए है।

231. (D) युधिष्ठिर
महाभारत के युद्ध की समाप्ति के बाद युधिष्ठिर मानसिक ग्लानि और वैराग्य से भरे हुए थे। उन्हें शासन की कला और राजा के उत्तरदायित्वों को समझाने के लिए श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह के पास भेजा। भीष्म ने सरशय्या पर लेटे हुए युधिष्ठिर को राजधर्म के सिद्धांतों, न्याय व्यवस्था, संकटकालीन नीतियों और मोक्ष के मार्ग के बारे में विस्तार से उपदेश दिया। यह संवाद ही शांति पर्व का मुख्य हिस्सा है, जो प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन का एक अमूल्य विश्वकोश माना जाता है। इसमें राजा के नैतिक और प्रशासनिक कर्तव्यों पर बल दिया गया है।

232. (A) संरक्षकों और सहायकों के बीच एकता को बढ़ावा देना और निजी हितों को समाप्त करना।
प्लेटो का मानना था कि निजी संपत्ति और पारिवारिक मोह मनुष्य में स्वार्थ और पक्षपात उत्पन्न करते हैं। एक दार्शनिक राजा और सैनिक को राज्य के प्रति पूर्णतः समर्पित होना चाहिए। साम्यवाद की इस व्यवस्था के माध्यम से प्लेटो चाहते थे कि शासक वर्ग किसी भी प्रकार के प्रलोभन से मुक्त रहे। जब उनकी अपनी कोई संपत्ति नहीं होगी, तो वे पूरे राज्य को अपना परिवार समझेंगे और निष्पक्ष होकर न्याय करेंगे। यह आदर्श राज्य की एकता सुनिश्चित करने और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए किया गया एक कठोर किंतु दार्शनिक उपाय था।

233. (C) धारित वस्तुओं के स्वरूपित वितरण का सिद्धांत।
रॉबर्ट नोज़िक ने तर्क दिया कि वितरण का कोई भी 'स्वरूपित' सिद्धांत अन्यायपूर्ण है क्योंकि वह व्यक्तियों की मेहनत के फल को उनकी सहमति के बिना छीन लेता है। उनके न्याय के सिद्धांत के तीन ऐतिहासिक स्तंभ हैं: वस्तुओं को न्यायपूर्ण तरीके से प्राप्त करना, उन्हें स्वेच्छा से दूसरों को सौंपना, और यदि कोई गलत तरीका अपनाया गया हो तो उसका सुधार करना। नोज़िक के अनुसार प्रक्रिया की न्यायसंगतता ही परिणाम की न्यायसंगतता को निर्धारित करती है, वितरण का कोई पूर्व-निश्चित पैटर्न व्यक्तिगत स्वतंत्रता और न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है।

234. (A) P-4, Q-3, R-1, S-2
जेरेमी बेंथम ने सुख को मापने के लिए सुखवादी गणना की विधि दी। इमैनुएल कांट ने 'निरपेक्ष आदेश' का नैतिक सिद्धांत प्रतिपादित किया, जो कर्तव्य पर आधारित है। जॉन रॉल्स ने 'भेद का सिद्धांत' दिया जो समाज के सबसे वंचित वर्गों के उत्थान पर केंद्रित है। ज्यां-जैक रूसो ने 'सामान्य इच्छा' के माध्यम से लोकप्रिय संप्रभुता का समर्थन किया। ये चारों अवधारणाएं राजनीतिक और नैतिक दर्शन के विकास में मील का पत्थर मानी जाती हैं और समाज की न्याय तथा शासन व्यवस्था को समझने के लिए अनिवार्य आधार प्रदान करती हैं।

235. (D) रेडिकल या नव मानवतावाद
एम.एन. रॉय का राजनीतिक जीवन विविध विचारधाराओं से होते हुए अंततः मौलिक मानवतावाद पर आकर स्थिर हुआ। वे मार्क्सवाद की यांत्रिकता और दलीय राजनीति के दोषों से निराश हो गए थे। उन्होंने तर्क दिया कि सच्चा लोकतंत्र तभी आ सकता है जब व्यक्ति स्वयं को तर्कसंगत और नैतिक बनाए। उनका यह दर्शन सत्ता के पूर्ण विकेंद्रीकरण, दलविहीन राजनीति और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सर्वोच्चता की वकालत करता है। रॉय ने मानवता को किसी भी वर्ग या राष्ट्र की सीमा से ऊपर मानकर व्यक्ति की गरिमा और विवेक को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया।

236. (B) समुदाय की सामान्य इच्छा, जो राज्य में अभिव्यक्ति पाती है क्योंकि यह सामान्य हित को बनाए रखती है।
टी.एच. ग्रीन के अनुसार नागरिक राज्य के प्रति आज्ञाकारी इसलिए होते हैं क्योंकि वे राज्य को अपने अधिकारों के संरक्षक के रूप में देखते हैं। राज्य का आधार बल प्रयोग नहीं, बल्कि नागरिकों की 'सहमति' और 'सामान्य हित' की चेतना है। ग्रीन का मानना था कि व्यक्ति का नैतिक दायित्व है कि वह उन नियमों का पालन करे जो समाज के सामूहिक कल्याण में सहायक हों। राज्य इसी सामूहिक इच्छा का संस्थागत रूप है, इसलिए नागरिकों का इसके प्रति आज्ञाकारिता का भाव स्वाभाविक और नैतिक है। यह राज्य की वैधता का आधार है।

Click Here to Buy book on Amazon

237. (C) रॉबर्ट नोजिक
रॉबर्ट नोजिक ने तर्क दिया कि एक विस्तृत राज्य अनिवार्य रूप से व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन करता है। उनके अनुसार केवल एक 'न्यूनतम राज्य' ही नैतिक रूप से उचित है। इस राज्य के कार्य अत्यंत सीमित होते हैं, जैसे नागरिकों को शारीरिक हिंसा, चोरी और अनुबंधों के उल्लंघन से बचाना। नोजिक के 'पहरेदार राज्य' का कार्य केवल सुरक्षा प्रदान करना है, उसे समाज के आर्थिक वितरण या लोगों के निजी नैतिक जीवन में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। यह विचार समकालीन उदारतावाद का एक प्रमुख आधार है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल देता है।

238. (D) 1, 2, और 3
जय प्रकाश नारायण का राजनीतिक सफर अत्यंत प्रभावशाली रहा है। वे अपनी युवावस्था में मार्क्सवाद और समाजवाद के कट्टर समर्थक थे। बाद में वे गांधीवादी विचारधारा की ओर मुड़े और भूदान तथा सर्वोदय आंदोलनों में सक्रिय भूमिका निभाई। 1970 के दशक में उन्होंने सत्ता की निरंकुशता के विरुद्ध 'संपूर्ण क्रांति' का आह्वान किया, जिसने भारतीय राजनीति की दिशा बदल दी। वे सत्ता के विकेंद्रीकरण और आम आदमी के सशक्तिकरण के प्रबल प्रस्तावक थे, जिसका उद्देश्य राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था में बुनियादी और नैतिक बदलाव लाना था।

239. (A) एंटोनियो ग्राम्शी
ग्राम्शी ने क्रांतियों के दो अलग-अलग तरीकों का विश्लेषण किया। 'गति का युद्ध' एक तेज और प्रत्यक्ष प्रहार है जो राज्य सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए किया जाता है। 'स्थिति का युद्ध' एक दीर्घकालिक और वैचारिक संघर्ष है जो नागरिक समाज की संस्थाओं (शिक्षा, मीडिया, धर्म) के भीतर लड़ा जाता है। ग्राम्शी का मानना था कि आधुनिक लोकतांत्रिक देशों में जहाँ शासक वर्ग का वर्चस्व मजबूत है, वहां क्रांति की सफलता के लिए पहले 'स्थिति का युद्ध' जीतना अनिवार्य है ताकि जनता की मानसिकता बदली जा सके और वैकल्पिक वर्चस्व बनाया जा सके।

240. (B) स्वयं पर शासन, या आत्म-नियंत्रण, जो सच्ची स्वतंत्रता की कुंजी है।
गांधी जी के लिए स्वराज केवल एक राजनीतिक स्थिति नहीं, बल्कि एक नैतिक साधना थी। उनका मानना था कि यदि हम स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख सकते, तो बाहरी स्वतंत्रता का कोई मूल्य नहीं है। स्वराज का अर्थ है—प्रत्येक व्यक्ति का स्वयं का स्वामी होना। जब व्यक्ति अपनी इंद्रियों और इच्छाओं को वश में कर लेता है, तो वह किसी भी बाहरी दबाव से मुक्त हो जाता है। गांधी जी के अनुसार इसी आत्म-शासन के आधार पर ही एक शोषण मुक्त, अहिंसक और न्यायपूर्ण स्वदेशी समाज का निर्माण संभव है जो मानवीय गरिमा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है।

241. (A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
कार्ल मार्क्स का मानना था कि समाज का विकास उत्पादन की शक्तियों के विकास के अनुसार होता है। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि जहाँ औद्योगिक क्रांति अपने शिखर पर होगी और पूंजीपति तथा सर्वहारा के बीच का अंतर्विरोध सबसे तीव्र होगा, वहीं क्रांति की पहली चिंगारी भड़केगी। ब्रिटेन और जर्मनी जैसे उन्नत पूंजीवादी देशों में पूंजी का अत्यधिक संचय और श्रमिकों का चरम शोषण मार्क्स के अनुसार क्रांति के लिए सबसे उपयुक्त वस्तुनिष्ठ स्थितियां पैदा कर रहा था। यह ऐतिहासिक विकास के भौतिकवादी नियमों पर आधारित एक वैज्ञानिक विश्लेषण था।

242. (A) लोगों का कल्याण और सुरक्षा सुनिश्चित करने से प्राप्त जन-समर्थन द्वारा।
कौटिल्य का मानना था कि राजा की वास्तविक शक्ति उसकी प्रजा की संतुष्टि में निहित है। यद्यपि वे एक शक्तिशाली राजतंत्र के समर्थक थे, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि राजा अत्याचारी हो जाता है और अपनी प्रजा की रक्षा नहीं कर पाता, तो वह अपना नैतिक अधिकार और सत्ता खो देता है। 'अर्थशास्त्र' में राजा को सलाह दी गई है कि वह प्रजा के हित में ही अपना हित देखे। जन-समर्थन ही वह आधार है जो राज्य को आंतरिक विद्रोहों से बचाता है और उसे सुदृढ़ बनाता है। प्रजा का अनुराग ही राज्य की अजेय शक्ति का मूल स्रोत है।

243. (C) समुदायवाद
समुदायवादी विचारक उदारवाद के इस विचार की आलोचना करते हैं कि व्यक्ति एक स्वतंत्र और पृथक इकाई है। वे 'सन्निहित स्व' की अवधारणा देते हैं, जिसका अर्थ है कि हमारी पहचान, उद्देश्य और नैतिकता हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों के भीतर ही निर्मित होते हैं। हम कौन हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस परिवार, धर्म और राष्ट्र का हिस्सा हैं। समुदायवादियों के अनुसार व्यक्ति को इन सामाजिक संबंधों से अलग करके देखना उसे उसकी वास्तविक मानवीय प्रकृति और अर्थपूर्ण जीवन से वंचित करना है। यह सामाजिक जुड़ाव पर बल देता है।

244. (D) आदर्शवाद
हेगेल का दर्शन पूर्णतः आदर्शवादी है क्योंकि उनका मानना है कि समस्त वास्तविकता का मूल आधार 'विचार' या 'चेतना' है। भौतिक जगत केवल इस परम चेतना की एक अभिव्यक्ति मात्र है। हेगेल ने तर्क दिया कि इतिहास तर्कसंगत है और यह विचारों के द्वंद्वात्मक विकास के माध्यम से सत्य की ओर बढ़ता है। उनके लिए राज्य, कानून और संस्कृति सभी एक महान ईश्वरीय योजना का हिस्सा हैं। यह विचारधारा भौतिकवादी दृष्टिकोण के पूर्णतः विपरीत है जो पदार्थ को प्राथमिक मानती है। हेगेल के लिए विचार ही जगत का सृष्टा और नियामक तत्व है।

245. (C) सरकार भंग हो जाती है और लोगों को एक नई सरकार स्थापित करने का अधिकार होता है।
जॉन लॉक के अनुसार सरकार एक न्यासी है जिसे जनता के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा का दायित्व सौंपा गया है। सरकार की शक्तियां असीमित नहीं हैं, बल्कि वे एक विशेष उद्देश्य के लिए सीमित हैं। यदि सरकार अत्याचारी बन जाती है या उन अधिकारों का हनन करने लगती है जिनकी रक्षा के लिए उसे बनाया गया था, तो वह अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन

NODIA

करती है। ऐसी स्थिति में जनता का नैतिक अधिकार है कि वह उस शासन को उखाड़ फेंके और अपनी सुरक्षा के लिए नई व्यवस्था करे। यह सहमति आधारित शासन और विद्रोह के अधिकार का सिद्धांत है।

246. (B) श्रमिकों का विभाजन।
डॉ. अंबेडकर का मानना था कि जाति व्यवस्था केवल कार्यों का विभाजन नहीं है, बल्कि यह मनुष्यों को स्थायी रुप से ऊंच-नीच के पदानुक्रम में विभाजित कर देती है। श्रम के सामान्य विभाजन में व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार कार्य बदल सकता है, लेकिन जाति व्यवस्था में व्यक्ति का कार्य उसके जन्म से ही तय हो जाता है। यह श्रमिकों की गतिशीलता और उनकी स्वतंत्रता को पूरी तरह समाप्त कर देती है। अंबेडकर के अनुसार यह व्यवस्था अप्राकृतिक है और समाज के आर्थिक व नैतिक विकास के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है जो समानता को नकारती है।

247. (D) डरा हुआ होना
मैकियावेली के अनुसार राजनीति में मानवीय भावनाएं अत्यंत अस्थिर होती हैं। लोग स्वार्थवश प्रेम करते हैं, लेकिन डर एक ऐसा बंधन है जो कभी नहीं टूटता क्योंकि इसमें दंड की निश्चितता होती है। उन्होंने शासक को सलाह दी कि यदि उसे प्रेम और भय में से किसी एक को चुनना हो, तो भय अधिक विश्वसनीय और सुरक्षित विकल्प है। हालांकि उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि राजा को डर तो पैदा करना चाहिए, लेकिन उसे क्रूर या अन्यायी बनकर अपनी प्रजा की घृणा मोल लेने से बचना चाहिए ताकि उसकी सत्ता और राज्य की स्थिरता बनी रहे।

248. (A) बेंथम केवल सुख की मात्रा पर विचार करते हैं, जबकि मिल गुणवत्ता पर भी विचार करते हैं।
जेरेमी बेंथम का मानना था कि सुखों को केवल उनकी तीव्रता और अवधि के आधार पर मापा जाना चाहिए। इसके विपरीत, जे.एस. मिल ने तर्क दिया कि कुछ सुख अपनी प्रकृति में उच्च श्रेणी के होते हैं। मिल के अनुसार बौद्धिक, कलात्मक और नैतिक आनंद शारीरिक सुखों से कहीं अधिक श्रेष्ठ हैं। उन्होंने कहा कि "एक संतुष्ट सूअर होने की तुलना में एक असंतुष्ट मनुष्य होना बेहतर है।" यह गुणात्मक अंतर मिल के उपयोगितावाद को केवल स्वार्थपूर्ण आनंद से ऊपर उठाकर मानवीय गरिमा के साथ जोड़ता है, जिससे यह एक उच्च नैतिक दर्शन बनता है।

249. (C) वी. आई. लेनिन
लेनिन की प्रसिद्ध कृति 'साम्राज्यवाद, पूंजीवाद का उच्चतम चरण' का यह मुख्य विषय है। उनका तर्क था कि जब पूंजीवाद में उत्पादन और पूंजी का संचय बहुत अधिक बढ़ जाता है, तो बैंक और उद्योग मिलकर 'वित्तीय पूंजी' का एकाधिकार स्थापित कर लेते हैं। यह एकाधिकारवादी पूंजी नए बाजारों और कच्चे माल के लिए पिछड़े देशों पर नियंत्रण करने को मजबूर होती है, जिसे साम्राज्यवाद कहा जाता है। लेनिन के अनुसार यह पूंजीवाद के अंतिम पतन और विश्व क्रांति की पूर्व संध्या का संकेत है। यह वैश्विक शोषण का एक संगठित और हिंसक रूप है।

250. (A) जॉन रॉल्स
जॉन रॉल्स ने अपने न्याय के सिद्धांत को 'निष्पक्षता के रूप में न्याय' कहा। उनका मानना था कि न्याय के सिद्धांतों का चुनाव ऐसी स्थिति में होना चाहिए जहाँ कोई भी पक्षपाती न हो सके। 'अज्ञानता के पर्दे' के पीछे व्यक्ति ऐसे नियमों का चयन करेंगे जो समाज के सबसे कमजोर सदस्यों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। रॉल्स का यह दर्शन उदारवाद और सामाजिक न्याय के बीच एक सेतु बनाने का प्रयास करता है, जहाँ व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आर्थिक समानता के बीच एक तार्किक संतुलन स्थापित किया गया है। यह आधुनिक राजनीतिक दर्शन का एक आधारभूत स्तंभ है।

251. (D) युद्ध
प्राचीन भारतीय कूटनीति और कौटिल्य के दर्शन में 'उपाय' उन चार तरीकों को कहते हैं जिनसे राजा अपने राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करता है। ये हैं: साम (संधि), दाम (उपहार), भेद (फूट डालना) और दंड (बल प्रयोग)। 'युद्ध' दंड का ही एक विस्तार है, लेकिन वह चार मूल उपायों की सूची में अलग से शामिल नहीं है। राजा को पहले तीन उपायों का उपयोग करना चाहिए और दंड को केवल अंतिम विकल्प के रूप में अपनाना चाहिए जब अन्य सभी तरीके विफल हो जाएं। यह शासन और कूटनीति के कुशल संचालन का एक व्यावहारिक ढांचा है।

252. (D) 1, 2, और 3
अरस्तू का राजनीतिक दर्शन यथार्थवाद और अनुभववाद पर आधारित है। उन्होंने दासता को एक प्राकृतिक संस्था माना जो स्वामी और दास दोनों के लिए उपयोगी थी। उनका मानना था कि राज्य का उदय विकास की एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो मनुष्य की सामाजिक आवश्यकताओं से प्रेरित है। अरस्तू ने 'संवैधानिक तंत्र' को शासन का सबसे स्थिर रूप बताया क्योंकि यह धनी और निर्धन वर्गों के बीच संतुलन बनाए रखता है और क्रांति की संभावनाओं को कम करता है। यह वर्गीकरण और विश्लेषण आज भी राजनीति विज्ञान में तुलनात्मक अध्ययन का आधार माना जाता है।

253. (C) माओ जेदोंग
माओ जेदोंग ने मार्क्सवाद-लेनिनवाद को चीन की ग्रामीण परिस्थितियों के अनुरूप ढाला। उनका मानना था कि चीन जैसे कृषि प्रधान देश में औद्योगिक श्रमिक कम हैं, इसलिए क्रांति का मुख्य केंद्र गांवों को होना चाहिए। उन्होंने 'दीर्घकालिक जनयुद्ध' की रणनीति दी, जिसके तहत क्रांतिकारी गाँवों को अपना सुरक्षित आधार बनाते हैं और फिर धीरे-धीरे शहरों को चारों ओर से घेर लेते हैं। यह रणनीतिक नवाचार 'माओवाद' का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है जिसने कई एशियाई क्रांतियों को प्रभावित किया और छापामार युद्ध की नई दिशा प्रदान की।

254. (A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
टी.एच. ग्रीन ने उदारवाद के दायरे को विस्तृत करते हुए सकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा पेश की। उनका तर्क था कि स्वतंत्रता केवल कानून की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि यह वह शक्ति है जो व्यक्ति को अपनी अंतर्निहित क्षमताओं को

Downloaded from www.pdf.tube

विकसित करने में मदद करती है। यदि कोई व्यक्ति गरीबी या बीमारी से लाचार है, तो वह वास्तव में स्वतंत्र नहीं है। राज्य का दायित्व है कि वह इन बाधाओं को दूर करके ऐसी परिस्थितियाँ बनाए जहाँ नागरिक नैतिक और बौद्धिक रूप से समृद्ध हो सकें। यह विचार कल्याणकारी राज्य के दार्शनिक आधार को पुख्ता करता है।

255. (A) व्यापक सामाजिक, राजनीतिक और नैतिक परिवर्तन के लिए एक कार्यक्रम।
जय प्रकाश नारायण द्वारा समर्थित संपूर्ण क्रांति का लक्ष्य केवल राजनीतिक सत्ता को बदलना नहीं था, बल्कि भारतीय समाज की जड़ों में व्याप्त भ्रष्टाचार और जड़ता को समाप्त करना था। वे एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते थे जहाँ शक्ति सीधे लोगों के हाथों में हो और सत्ता का पूर्ण विकेंद्रीकरण हो। इस क्रांति में सात आयाम शामिल थे जो मानवीय जीवन के सर्वांगीण विकास पर केंद्रित थे। यह आंदोलन नागरिकों की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से लोकतंत्र को पुनः जीवंत करने और सामाजिक न्याय स्थापित करने का एक महान ऐतिहासिक प्रयास था।

256. (B) दार्शनिक-राजाओं द्वारा।
प्लेटो के आदर्श राज्य में शासन का अधिकार केवल उन लोगों को है जिन्होंने अपनी बुद्धि और विवेक को सर्वोच्च स्तर तक विकसित किया है। 'दार्शनिक राजा' वह है जिसे 'शुभ के विचार' का पूर्ण ज्ञान है और जो स्वार्थ या संपत्ति के प्रलोभन से मुक्त है। प्लेटो का मानना था कि जब तक राजा दार्शनिक नहीं होंगे, तब तक राज्यों में बुराइयां और अशांति समाप्त नहीं होगी। उनका शासन लिखित कानून के बजाय उनके उत्कृष्ट विवेक और ज्ञान पर आधारित होता है। यह व्यवस्था राज्य में न्याय और सद्भाव सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई थी।

257. (B) रूसो
ज्यां-जैक रूसो ने तर्क दिया कि 'सामान्य इच्छा' सदैव सामूहिक हित और न्याय की ओर निर्देशित होती है, इसलिए वह कभी गलत नहीं हो सकती। हालांकि, उन्होंने यह भी माना कि जनता कभी-कभी भ्रमित हो सकती है और यह नहीं पहचान पाती कि वास्तव में उसका भला किसमें है। इसीलिए रूसो ने एक 'विधायक' की भूमिका की बात की जो जनता को सही रास्ता दिखा सके। उनका दर्शन यह स्पष्ट करता है कि लोकप्रिय संप्रभुता को सदैव तर्कसंगतता और सार्वजनिक भलाई के उद्देश्यों से प्रेरित होना चाहिए। यह इच्छा ही राज्य की वास्तविक शक्ति का स्रोत है।

258. (A) उत्पादन के साधनों के स्वामियों और संपत्तिहीन श्रमिकों के बीच।
कार्ल मार्क्स के अनुसार इतिहास की मुख्य प्रेरक शक्ति वर्ग संघर्ष है। पूंजीवादी समाज में यह संघर्ष मुख्य रूप से 'बुर्जुआ' (पूंजीपति) और 'सर्वहारा' (श्रमिक) के बीच होता है। पूंजीपति उत्पादन के साधनों का मालिक होता है और श्रमिकों का शोषण करके लाभ कमाता है। श्रमिक के पास केवल अपना श्रम होता है जिसे वह जीवित रहने के लिए बेचने को मजबूर होता है। मार्क्स का मानना था कि यह अंतर्निहित संघर्ष ही अंततः पूंजीवाद के पतन और एक वर्गहीन साम्यवादी समाज के उदय का कारण बनेगा। यह ऐतिहासिक परिवर्तन का द्वंद्वात्मक नियम है।

259. (C) शांति पर्व और अर्थशास्त्र
सप्तांग सिद्धांत प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की एक विशिष्ट विशेषता है जो राज्य के सात अनिवार्य अंगों का वर्णन करती है। ये अंग—स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र—राज्य की स्थिरता और शक्ति के लिए आवश्यक माने गए हैं। इसका विस्तृत उल्लेख महाभारत के शांति पर्व और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। यह सिद्धांत राज्य को एक जैविक इकाई के रूप में देखता है जहाँ प्रत्येक अंग का अपना महत्व है और वे मिलकर समाज में शांति, सुरक्षा और सुचारु शासन व्यवस्था सुनिश्चित करते हैं। यह शासन व्यवस्था का पूर्ण ढांचा है।

260. (D) संसदीय लोकतंत्र और साम्यवाद दोनों के।
एम.एन. रॉय का राजनीतिक जीवन विविध विचारधाराओं से होते हुए अंततः मौलिक मानवतावाद पर समाप्त हुआ। अपने उत्तरवर्ती वर्षों में वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि संसदीय लोकतंत्र केवल एक दिखावा है जहाँ वास्तविक सत्ता कुछ लोगों के हाथ में होती है। साथ ही वे साम्यवादी तानाशाही के भी विरोधी बन गए क्योंकि वहां व्यक्तिगत स्वतंत्रता पूरी तरह समाप्त हो गई थी। उन्होंने एक ऐसे 'दलविहीन लोकतंत्र' की वकालत की जहाँ सत्ता सीधे लोगों की परिषदों के पास हो और व्यक्ति की तर्कशक्ति सर्वोपरि हो। यह दर्शन मानवीय गरिमा को केंद्र में रखता है।

261. (A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
समुदायवादी विचारक जैसे माइकल सैंडेल का तर्क है कि उदारवादी व्यक्तिवाद मनुष्य की सामाजिक प्रकृति की उपेक्षा करता है। वे मानते हैं कि व्यक्ति कोई 'खाली स्लेट' नहीं है जो समाज से अलग अपने अधिकारों का चुनाव करे। हमारी पहचान, नैतिकता और जीवन के उद्देश्य हमारे समुदाय, परिवार और संस्कृति के साझा मूल्यों से गहराई से जुड़े होते हैं। इसलिए समुदायवादियों के अनुसार, अधिकारों की चर्चा साझा भलाई और उन सामाजिक संदर्भों से अलग होकर नहीं की जा सकती जो हमें अर्थ प्रदान करते हैं। यह व्यक्ति और समाज के अटूट संबंध पर बल देता है।

262. (A) P-4, Q-3, R-1, S-2
महात्मा गांधी ने आर्थिक समानता के लिए न्यासिता का सिद्धांत दिया। डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने जाति व्यवस्था के पूर्ण उन्मूलन के लिए 'जाति का विनाश' की मांग की। वी.डी. सावरकर ने 'हिंदुत्व' को एक राजनीतिक और सांस्कृतिक पहचान के रूप में स्थापित किया। एम.एन. रॉय ने अपने अंतिम वर्षों में मौलिक मानवतावाद का प्रतिपादन किया। ये चारों विचारधाराएं आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन की विविधता को प्रदर्शित करती हैं, जिन्होंने देश के सामाजिक ढांचे को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये विचार भारतीय आधुनिकता और सुधार आंदोलन के महत्वपूर्ण स्तंभ माने जाते हैं।

NODIA

263. (D) आधुनिक स्वतंत्रता
जे.एस. मिल के विचार आधुनिक स्वतंत्रता के सशक्त बचाव पर केंद्रित हैं, विशेष रूप से विचार, अभिव्यक्ति और व्यक्तिगत स्वायत्तता की स्वतंत्रता पर। उनका मानना था कि व्यक्ति को अपनी जीवनशैली चुनने और अपने विचारों को व्यक्त करने का पूर्ण अधिकार होना चाहिए, बशर्ते वह दूसरों को प्रत्यक्ष हानि न पहुँचाए। मिल ने "बहुमत की निरंकुशता" के खतरों के प्रति चेतावनी दी और तर्क दिया कि एक सभ्य समाज की पहचान उसकी विविधता और व्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति सम्मान में ही निहित है। यह सिद्धांत व्यक्तिगत स्वतंत्रता को समाज की प्रगति के लिए अनिवार्य मानता है।

264. (A) जॉन लॉक
जॉन लॉक के अनुसार संपत्ति का अधिकार एक बुनियादी प्राकृतिक अधिकार है जो राज्य के निर्माण से भी पहले का है। उनका तर्क था कि प्रकृति ने संसाधन सभी को दिए हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति उन संसाधनों के साथ अपना शारीरिक श्रम सम्मिलित करता है, तो वह वस्तु उसकी निजी संपत्ति बन जाती है। लॉक का यह श्रम सिद्धांत व्यक्तिगत स्वामित्व और आधुनिक उदारवादी अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख आधार बना। उनके अनुसार सरकार का मुख्य कार्य इसी निजी संपत्ति के अधिकार की रक्षा करना है। यह व्यक्ति की मेहनत और उसके प्रतिफल को न्यायसंगत ठहराने वाला एक क्रांतिकारी विचार था।

265. (A) 2, 1, 3, 4
इन महान विचारकों का कालक्रम राजनीतिक दर्शन के ऐतिहासिक विकास को दर्शाता है। अरस्तू प्राचीन यूनान के विचारक थे जिन्होंने शासन के वैज्ञानिक वर्गीकरण की नींव रखी। निकोलो मैकियावेली पुनर्जागरण काल के थे जिन्होंने आधुनिक यथार्थवाद की शुरुआत की। जॉन लॉक 17वीं शताब्दी के प्रबोधन काल के विचारक थे जिन्होंने उदारवाद और प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत दिया। अंत में कार्ल मार्क्स 19वीं शताब्दी के थे जिन्होंने पूंजीवाद की आलोचना और वर्ग संघर्ष का विचार प्रस्तुत किया। यह क्रम राजनीतिक चिंतन में आदर्शवाद से यथार्थवाद और फिर भौतिकवाद की यात्रा को स्पष्ट करता है।

266. (A) भारत को अपनी पुण्यभूमि मानना।
सावरकर के हिंदुत्व सिद्धांत के अनुसार 'हिंदू' होने के लिए भारत को केवल पितृभूमि मानना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसे 'पुण्यभूमि' मानना भी अनिवार्य है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति के धर्म का जन्म और उसके तीर्थ स्थल भारत की भौगोलिक सीमा के भीतर होने चाहिए। सावरकर का यह मानदंड ईसाई और मुस्लिम धर्मावलंबियों को हिंदुत्व की इस विशिष्ट परिभाषा से बाहर रखता है, भले ही वे भारत में पैदा हुए हों और इसे अपनी मातृभूमि मानते हों। यह हिंदुत्व को एक विशिष्ट सांस्कृतिक और राष्ट्रीय पहचान के रूप में स्थापित करने का प्रयास था जो साझा धार्मिक जड़ों पर आधारित है।

267. (D) हेगेल
हेगेल ने राज्य को एक दिव्य संस्था और सर्वोच्च नैतिक सत्ता के रूप में देखा। उनका मानना था कि राज्य केवल एक राजनीतिक व्यवस्था नहीं है, बल्कि यह सार्वभौमिक तर्क और नैतिकता का पृथ्वी पर साक्षात अवतार है। व्यक्ति को अपनी वास्तविक स्वतंत्रता और सार्थकता केवल राज्य के सदस्य के रूप में ही प्राप्त हो सकती है। हेगेल का यह विचार राज्य को एक सर्वशक्तिमान और पवित्र स्थान प्रदान करता है, जो मानवीय हितों और व्यक्तिगत अधिकारों से कहीं अधिक उच्च माना गया है। उनके लिए राज्य के प्रति निष्ठा ही व्यक्ति के नैतिक जीवन की चरम परिणति है। यह आदर्शवादी चिंतन का शिखर है।

268. (B) बल और सहमति के संयोजन के माध्यम से।
एंटोनियो ग्राम्शी ने तर्क दिया कि आधुनिक पूंजीवादी राज्य केवल पुलिस और सेना के बल पर नहीं टिका है। शासक वर्ग नागरिक समाज के माध्यम से अपनी विचारधारा को समाज में फैलाता है और लोगों की सक्रिय सहमति प्राप्त करता है जिसे 'वर्चस्व' कहा जाता है। जब लोग शासक वर्ग के मूल्यों को स्वाभाविक और सही मानकर स्वीकार कर लेते हैं, तब राज्य का नियंत्रण अधिक सुदृढ़ हो जाता है। अतः राज्य की सत्ता बल और सहमति के सूक्ष्म संतुलन पर आधारित होती है। यह वैचारिक नियंत्रण दमनकारी शक्ति से अधिक प्रभावी होता है क्योंकि यह जनमानस को अंदर से प्रभावित करता है।

269. (C) नागरिकों को अपना स्थान स्वीकार करने और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए सहमत करना।
प्लेटो के 'धातुओं के मिथक' का उद्देश्य समाज में व्यवस्था और स्थिरता बनाए रखना था। इसमें लोगों को यह बताया जाता है कि ईश्वर ने प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा में एक विशिष्ट धातु—सोना, चांदी या पीतल—मिलाया है। इसका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना था कि प्रत्येक नागरिक अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कार्य को बिना किसी विद्रोह के स्वीकार करे। यह मिथक राज्य की कार्यात्मक विशेषज्ञता और वर्ग संरचना को एक 'दैवीय' तथा 'प्राकृतिक' आधार प्रदान करता था ताकि समाज में संघर्ष न हो और न्याय की स्थापना हो सके। यह शासकों द्वारा राज्य की एकता के लिए दिया गया एक सामूहिक संदेश था।

270. (A) केवल 1 और 3
थॉमस हॉब्स के सामाजिक अनुबंध में लोग आपस में समझौता करके एक संप्रभु सत्ता का निर्माण करते हैं, लेकिन संप्रभु स्वयं इस अनुबंध का हिस्सा नहीं होता। इसलिए उस पर अनुबंध की शर्तें लागू नहीं होतीं और उसकी शक्ति असीमित रहती है। हालांकि, चूंकि अनुबंध का मूल उद्देश्य ही जीवन की रक्षा करना है, इसलिए प्रजा के पास अपने आत्म-संरक्षण का बुनियादी अधिकार बना रहता है। यदि संप्रभु प्रजा के जीवन के लिए सीधा खतरा पैदा करता है, तो ऐसी असाधारण स्थिति में प्रजा को उसकी आज्ञा न मानने का अधिकार सुरक्षित होता है। यह हॉब्स के दर्शन में व्यक्तिगत सुरक्षा को दी गई एकमात्र और सर्वोच्च प्राथमिकता है।

Click Here to Buy book on Amazon

271. (A) आत्म-खोज की अवधि, कार्रवाई की अवधि और आत्म-साक्षात्कार की अवधि।
अरविंदो घोष ने भारत के राष्ट्रीय जागरण को एक आध्यात्मिक प्रक्रिया के रूप में देखा। उनके अनुसार पहले चरण में राष्ट्र को अपनी प्राचीन संस्कृति और शक्ति की 'आत्म-खोज' करनी होती है। दूसरे चरण में वह राजनीतिक संघर्ष और प्रतिरोध के माध्यम से अपनी पहचान स्थापित करने के लिए 'कार्रवाई' करता है। अंतिम चरण में राष्ट्र अपनी पूर्ण स्वतंत्रता और आध्यात्मिक गरिमा को प्राप्त करके 'आत्म-साक्षात्कार' करता है। अरविंदो का मानना था कि भारत का पुनरुत्थान पूरी मानवता के आध्यात्मिक विकास के लिए एक ईश्वरीय योजना का हिस्सा है। यह राष्ट्रवाद को एक धार्मिक और दिव्य कर्तव्य के रूप में प्रस्तुत करता है।

272. (B) समान बुनियादी स्वतंत्रता का सिद्धांत।
जॉन रॉल्स के अनुसार उनके द्वारा प्रस्तावित न्याय के सिद्धांतों के बीच एक निश्चित प्राथमिकता का क्रम है। प्रथम सिद्धांत, जो सभी के लिए समान बुनियादी स्वतंत्रताएं सुनिश्चित करता है, उसे सर्वोच्च वरीयता प्राप्त है। इसका अर्थ है कि आर्थिक लाभ या सामाजिक कल्याण के नाम पर किसी व्यक्ति की बुनियादी स्वतंत्रता के साथ समझौता नहीं किया जा सकता। रॉल्स का मानना था कि एक न्यायपूर्ण समाज में स्वतंत्रता का स्थान सर्वोपरि है और इसे केवल स्वतंत्रता की रक्षा के लिए ही सीमित किया जा सकता है। यह उदारवादी न्याय दर्शन का मूल आधार है जो व्यक्तिगत स्वायत्तता को किसी भी सामूहिक हित से ऊपर रखता है।

273. (B) उसकी राष्ट्रीय पहचान से।
कार्ल मार्क्स के अलगाव के सिद्धांत में राष्ट्रीय पहचान का कोई स्थान नहीं है; वे वर्ग पहचान को ही प्राथमिक मानते थे। अलगाव के चार मुख्य रूप हैं: उत्पाद से अलगाव, उत्पादन की प्रक्रिया से, साथी मनुष्यों से और स्वयं के मानवीय सार से। मार्क्स का मानना था कि पूंजीवाद मनुष्य की रचनात्मकता को छीनकर उसे केवल एक साधन बना देता है, जो एक गहरा मानवीय संकट है। श्रमिक स्वयं को अपनी मेहनत के फल से दूर पाता है और काम उसे थकावट के सिवा कुछ नहीं देता। यह प्रक्रिया मनुष्य को उसकी अपनी प्रकृति से ही विमुख कर देती है, जिससे वह समाज में एकाकी और रिक्त महसूस करता है।

274. (A) जेरेमी बेंथम
जेरेमी बेंथम सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के कड़े आलोचक थे और उन्होंने इसे "तर्कहीन" माना। वे उपयोगितावाद के प्रणेता थे और उनका मानना था कि राज्य की वैधता का आधार कोई ऐतिहासिक या काल्पनिक अनुबंध नहीं, बल्कि उसकी 'उपयोगिता' है। यदि राज्य अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख सुनिश्चित करता है, तो वह वैध है। इसके विपरीत हॉब्स, लॉक और रूसो तीनों ने राज्य की उत्पत्ति और वैधता को लोगों के बीच हुए एक मूल समझौते या सामाजिक अनुबंध के माध्यम से समझाने का प्रयास किया था। बेंथम ने अधिकारों को कानूनी सत्ता की उपज माना, न कि प्रकृति की, जो उनके यथार्थवादी और व्यावहारिक दृष्टिकोण को दर्शाता है।

275. (C) प्राकृतिक दास और स्वामी दोनों के लिए स्वाभाविक और हितकारी।
अरस्तू ने दासता को समाज के लिए अनिवार्य और तर्कसंगत माना। उनके अनुसार कुछ व्यक्ति मानसिक रूप से इतने दुर्बल होते हैं कि वे स्वयं का मार्गदर्शन नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें एक विवेकपूर्ण स्वामी के अधीन रहना चाहिए। दासता से स्वामी को वह अवकाश मिलता है जो दार्शनिक और राजनीतिक गतिविधियों के लिए आवश्यक है। दास को अपने स्वामी के संपर्क में रहने से विवेक का मार्गदर्शन प्राप्त होता है। यह विचार आधुनिक समानता और मानवाधिकारों के सिद्धांतों के पूर्णतः विपरीत और आलोचना का विषय रहा है। अरस्तू का यह दृष्टिकोण उनकी सामाजिक व्यवस्था की स्थिरता और बौद्धिक उत्कर्ष की आवश्यकता पर आधारित था।

276. (A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
कार्ल मार्क्स का मानना था कि क्रांति सबसे उन्नत पूंजीवादी देशों में होगी, लेकिन लेनिन ने इसमें संशोधन किया। लेनिन ने तर्क दिया कि विश्व पूंजीवाद की श्रृंखला वहां टूटेगी जहाँ वह सबसे कमजोर है। रूस एक पिछड़ा हुआ और अर्ध-सामंती देश था, लेकिन वहां के अंतर्विरोध अत्यंत तीव्र थे। लेनिन ने इसी 'दुर्बल कड़ी' के सिद्धांत का उपयोग करके रूस में सर्वहारा क्रांति का नेतृत्व किया और यह साबित किया कि एक कम विकसित देश में भी समाजवादी परिवर्तन संभव है यदि वहां एक संगठित और अनुशासित क्रांतिकारी दल मौजूद हो। यह मार्क्सवाद का रूसी परिस्थितियों में एक सफल और रणनीतिक अनुप्रयोग था जिसने इतिहास बदल दिया।

277. (C) काम, क्रोध, लोभ, मान, मद और हर्ष।
प्राचीन भारतीय राजनीति शास्त्र और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजा को इन छह आंतरिक शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने की सलाह दी गई है। माना जाता था कि एक राजा जो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वह प्रजा और राज्य का सही संचालन भी नहीं कर पाएगा। ये आंतरिक दोष राजा के विवेक को नष्ट कर देते हैं और उसे अन्यायपूर्ण निर्णय लेने के लिए प्रेरित करते हैं। आत्म-संयम ही वह गुण है जो एक राजा को सच्चा शासक और प्रजा का रक्षक बनाता है। इंद्रिय विजय को राजधर्म की पहली सीढ़ी माना गया है क्योंकि एक अनुशासित राजा ही समाज में अनुशासन और न्याय की स्थापना करने में समर्थ हो सकता है।

278. (B) उन्होंने मानवीय नैतिकता को भ्रष्ट किया है और असमानता को जन्म दिया है।
रूसो ने अपनी शुरुआती रचना में तर्क दिया कि विज्ञान और कलाओं के विकास ने मनुष्य की सहज सरलता और नैतिकता को नष्ट कर दिया है। जैसे-जैसे सभ्यता आगे बढ़ी, विलासिता और आडंबर बढ़ते गए, जिससे समाज में भ्रष्टाचार और असमानता पैदा हुई। रूसो के अनुसार आधुनिक मनुष्य अपनी प्राकृतिक अच्छाई खो चुका है और केवल दूसरों को प्रभावित करने के लिए जीता है। वे 'प्रकृति की ओर लौटने' का आह्वान करते हैं ताकि मनुष्य पुनः अपनी सादगी और वास्तविक स्वतंत्रता को प्राप्त कर सके। यह विचार आधुनिक प्रगति के दावों पर एक

NODIA

गंभीर प्रहार था और मानवीय मूल्यों की पुनर्स्थापना का संदेश देता था।

279. (D) राजा के कर्तव्य, शासन और मोक्ष का मार्ग।
महाभारत का शांति पर्व भारतीय राजनीतिक चिंतन का एक अमूल्य स्रोत है। इसमें युद्ध के बाद पितामह भीष्म युधिष्ठिर को राजधर्म, आपद्धर्म (संकटकालीन नीतियां) और मोक्षधर्म के बारे में विस्तार से उपदेश देते हैं। यह ग्रंथ न केवल कूटनीति और दंडनीति की बात करता है, बल्कि यह राजा के व्यक्तिगत चरित्र, नैतिकता और प्रजा के कल्याण को भी शासन का केंद्र मानता है। यह भौतिक व्यवस्था और आध्यात्मिक शांति के बीच के गहन संबंधों का एक दार्शनिक अन्वेषण है। शांति पर्व में वर्णित राजधर्म एक न्यायपूर्ण और धर्मपरायण समाज के निर्माण की रूपरेखा प्रस्तुत करता है जो राजा को प्रजा के प्रति पूर्णतः उत्तरदायी बनाता है।

280. (A) प्रतिनिधि सरकार
जे.एस. मिल के अनुसार प्रतिनिधि सरकार ही शासन का वह रूप है जो आधुनिक सभ्य समाजों के लिए सबसे उपयुक्त है। उनके अनुसार यह व्यवस्था नागरिकों को राजनीतिक जीवन में भाग लेने का अवसर देती है जिससे उनकी बौद्धिक और नैतिक क्षमताओं का विकास होता है। हालांकि मिल ने "बहुमत की निरंकुशता" के प्रति आगाह किया और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व और बहुल मतदान जैसे उपायों का सुझाव दिया। उनका मानना था कि एक जागरूक समाज में ही प्रतिनिधि लोकतंत्र वास्तविक सफलता प्राप्त कर सकता है। यह शासन प्रणाली व्यक्ति की गरिमा और सामूहिक विवेक के बीच एक सेतु का कार्य करती है।

281. (B) P-4, Q-2, R-3, S-1
एंटोनियो ग्राम्शी ने वर्चस्व को नैतिक और वैचारिक नेतृत्व के रूप में देखा जो सहमति पर आधारित है। नागरिक समाज वह क्षेत्र है जहाँ चर्च और स्कूल जैसे संस्थान इस सहमति का निर्माण करते हैं। 'स्थिति का युद्ध' एक दीर्घकालिक संघर्ष है जिसका उद्देश्य मौजूदा वर्चस्व को धीरे-धीरे कमजोर करना है। 'जैविक बुद्धिजीवी' वे विचारक हैं जो अपने वर्ग के हितों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं और क्रांति के लिए जनचेतना जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये अवधारणाएं मार्क्सवाद के सांस्कृतिक और वैचारिक विश्लेषण का आधार हैं जो केवल आर्थिक कारणों के बजाय विचारों की शक्ति पर बल देती हैं। यह आधुनिक सत्ता को समझने का नया नजरिया है।

282. (A) राजनीतिक अधिकार के उद्देश्य और औचित्य की व्याख्या करना।
प्राकृतिक अवस्था एक ऐसी काल्पनिक स्थिति है जहाँ कोई सरकार या कानून नहीं होता। हॉब्स, लॉक और रूसो जैसे विचारकों ने इस अवधारणा का उपयोग यह समझाने के लिए किया कि मनुष्य ने राज्य का निर्माण क्यों किया और सरकार की शक्तियां किन शर्तों पर आधारित होनी चाहिए। यह विधि यह समझने में मदद करती है कि समाज में रहने के क्या लाभ हैं और नागरिकों को राज्य के प्रति अपनी आज्ञाकारिता के बदले में क्या प्राप्त होता है। यह राजनीतिक वैधता और दायित्व का एक दार्शनिक आधार तैयार करती है। यह हमें सिखाती है कि राज्य का मुख्य उद्देश्य अराजकता को समाप्त करना और व्यक्ति के अधिकारों तथा सुरक्षा को सुनिश्चित करना है।

NODIA

283. (D) जी.डब्ल्यू.एफ. हेगेल
हेगेल का यह प्रसिद्ध कथन उनके आदर्शवादी दर्शन का सार है। इसका तात्पर्य है कि विश्व इतिहास का क्रमिक विकास कोई आकस्मिक घटना नहीं है, बल्कि वह एक तर्कसंगत योजना का हिस्सा है। जो कुछ भी वास्तव में अस्तित्व में है, वह परम आत्मा की प्रगति का परिणाम है, इसलिए वह तर्कसंगत है। इसी प्रकार, जो विचार तर्कसंगत हैं, वे अनिवार्य रूप से भौतिक रूप में साकार होते हैं। यह विचार इतिहास और वास्तविकता को एक व्यवस्थित और उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत करता है। हेगेल के अनुसार संपूर्ण विश्व विवेक का ही प्रकटीकरण है, जहाँ प्रत्येक घटना सत्य की ओर ले जाने वाली एक आवश्यक कड़ी होती है। यह दर्शन को पूर्णता प्रदान करता है।

284. (C) केवल 3
माइकल वाल्ज़र एक प्रमुख समुदायवादी विचारक हैं जिन्होंने अपनी पुस्तक 'स्फेयर्स ऑफ जस्टिस' में तर्क दिया कि न्याय की कोई एक सार्वभौमिक परिभाषा नहीं हो सकती। उनके अनुसार प्रत्येक समाज और संस्कृति की अपनी विशिष्ट वस्तुएं और उनके अर्थ होते हैं, इसलिए उनके वितरण के नियम भी स्थानीय और ऐतिहासिक संदर्भों पर आधारित होने चाहिए। वाल्ज़र का यह दृष्टिकोण जॉन रॉल्स जैसे उदारवादियों की आलोचना करता है जो न्याय के ऐसे सिद्धांतों की खोज करते हैं जो सभी पर समान रूप से लागू हो सकें। वे मानते हैं कि न्याय की समझ सामाजिक मूल्यों और सांस्कृतिक विशिष्टताओं से जुड़ी होनी चाहिए। यह न्याय के प्रति एक बहुलवादी और संदर्भ-आधारित दृष्टिकोण है।

285. (C) व्यक्तियों के बीच सामाजिक संबंधों को वस्तुओं के बीच संबंधों के रूप में देखना।
कार्ल मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी समाज में वस्तुओं का मूल्य उनके मानवीय उपयोग के बजाय उनके विनिमय मूल्य से तय होता है। उत्पादन की प्रक्रिया में लगा श्रमिक और उपभोक्ता एक-दूसरे से सीधे नहीं जुड़ते, बल्कि बाजार के माध्यम से जुड़ते हैं। इसके परिणामस्वरूप, लोगों के बीच के वास्तविक मानवीय और सामाजिक संबंध अदृश्य हो जाते हैं और ऐसा लगने लगता है कि वस्तुओं के बीच ही कोई जादुई संबंध है। मार्क्स ने इसे 'वस्तु पूजा' कहा, जो पूंजीवाद में मानवीय चेतना के विकृत होने का प्रतीक है। यह प्रक्रिया मनुष्य को उसके श्रम की गरिमा से विमुख कर देती है और सामाजिक यथार्थ को केवल आर्थिक लेनदेन में सीमित कर देती है।

286. (D) कौटिल्य शासन-कला पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि प्लेटो न्याय और नैतिकता पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
प्लेटो का पूरा राजनीतिक दर्शन एक 'आदर्श राज्य' और 'न्याय' की खोज पर आधारित है जहाँ नैतिकता ही शासन का आधार है। इसके विपरीत, कौटिल्य का दृष्टिकोण अत्यंत यथार्थवादी और व्यावहारिक है। उनका मुख्य उद्देश्य राज्य की शक्ति, सुरक्षा

और विस्तार को सुनिश्चित करना है। यद्यपि कौटिल्य धर्म का सम्मान करते हैं, लेकिन वे कूटनीति और शासन-कला में राज्य के हित को किसी भी नैतिक सीमा से ऊपर रखते हैं। प्लेटो दार्शनिक पक्ष पर बल देते हैं, जबकि कौटिल्य प्रशासनिक और रणनीतिक पक्ष पर। जहाँ प्लेटो राजा को एक ऋषि बनाना चाहते थे, वहीं कौटिल्य उसे एक कुशल कूटनीतिज्ञ और रक्षक के रूप में देखते थे। यह दोनों के दृष्टिकोणों का मूलभूत अंतर है।

287. (A) इसका तात्पर्य एक अत्यधिक केंद्रीकृत और शक्तिशाली सरकार है।
महात्मा गांधी का 'राम राज्य' का विचार एक विकेंद्रीकृत और नैतिक समाज की कल्पना है, जहाँ सत्ता का कोई एक केंद्र नहीं होता। यह एक ऐसा आदर्श है जहाँ शासन भय के बजाय 'सत्य' और 'अहिंसा' पर आधारित होता है। राम राज्य में प्रत्येक व्यक्ति स्वयं पर पूर्ण नियंत्रण रखता है, जिससे राज्य के दमनकारी तंत्र की आवश्यकता न्यूनतम रह जाती है। गांधी जी इसे जनता की वास्तविक संप्रभुता का प्रतीक मानते थे, जहाँ शोषण का पूर्ण अभाव होता है और समाज का आधार प्रेम, सहयोग और निस्वार्थ सेवा होता है। यह केंद्रीकृत शक्ति के पूर्णतः विपरीत एक लोक-केंद्रित व्यवस्था है जो मानवीय गरिमा को सर्वोच्च मानती है।

288. (B) एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के दमन का एक साधन।
लेनिन ने मार्क्सवादी सिद्धांतों को आगे बढ़ाते हुए तर्क दिया कि राज्य कोई तटस्थ संस्था नहीं है। समाज में जब तक वर्ग रहेंगे, तब तक राज्य का उपयोग शक्तिशाली वर्ग द्वारा कमजोर वर्ग को दबाने के लिए किया जाता रहेगा। पूंजीवादी समाज में राज्य बुर्जुआ वर्ग का हथियार है, जबकि क्रांति के बाद 'सर्वहारा वर्ग की तानाशाही' में इसका उपयोग पूंजीवाद के अवशेषों को मिटाने और समाज को वर्गहीन बनाने के लिए किया जाएगा। लेनिन का मानना था कि एक पूर्ण साम्यवादी समाज में राज्य की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी और वह स्वतः तिरोहित हो जाएगा। यह राज्य के दमनकारी चरित्र को समाप्त करके वास्तविक समानता की स्थापना का पथ है।

289. (B) दूसरों के साथ मिलकर आत्म-साक्षात्कार के लिए कार्य करने की शक्ति।
टी.एच. ग्रीन के अनुसार सकारात्मक स्वतंत्रता केवल बंधनों की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि यह वह रचनात्मक क्षमता है जो व्यक्ति को समाज के सामान्य हित में योगदान देने के योग्य बनाती है। यह एक ऐसी स्वतंत्रता है जो केवल सामाजिक संदर्भ में ही प्राप्त की जा सकती है जहाँ लोग एक-दूसरे के विकास में सहायक होते हैं। ग्रीन का मानना था कि व्यक्ति की सच्ची स्वतंत्रता उसके नैतिक उत्कर्ष और अपनी अंतर्निहित संभावनाओं को साकार करने में निहित है, जिसके लिए राज्य को शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी अनुकूल परिस्थितियाँ निर्मित करनी चाहिए। यह विचार व्यक्तिगत अधिकारों को सामाजिक उत्तरदायित्व के साथ जोड़कर स्वतंत्रता को एक नई दिशा देता है।

290. (A) मैकियावेली
निकोलो मैकियावेली ने अपने इन दो प्रमुख ग्रंथों में शासन के अलग-अलग रूपों और परिस्थितियों का विश्लेषण किया। 'द प्रिंस' में उन्होंने इटली की तत्कालीन अराजकता को समाप्त करने के लिए एक शक्तिशाली और रणनीतिक शासक की आवश्यकता पर बल दिया जो किसी भी साधन से राज्य को सुरक्षित रख सके। वहीं 'द डिस्कोर्स' में उन्होंने प्राचीन रोम का उदाहरण देते हुए गणतंत्र को सरकार का सबसे उत्कृष्ट और स्थिर रूप माना, जहाँ नागरिक स्वतंत्रता और कानून का शासन सर्वोपरि होता है। ये दोनों कृतियाँ मिलकर मैकियावेली के समग्र राजनीतिक दर्शन को स्पष्ट करती हैं जो यथार्थवाद और देशभक्ति पर आधारित है।

291. (A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
एम.एन. रॉय का मानना था कि मनुष्य का विवेक या तर्क ही उसकी स्वतंत्रता का मूल स्रोत है। उनके अनुसार तर्कसंगतता मनुष्य को किसी भी बाह्य सत्ता या धार्मिक आदेश के बिना सही और गलत के बीच भेद करने में सक्षम बनाती है। इसी आधार पर वे एक ऐसे समाज की कल्पना करते थे जहाँ व्यक्ति स्वयं अपने भाग्य का विधाता हो। रॉय का मौलिक मानवतावाद नैतिकता को तर्कसंगतता से जोड़ता है, जिससे समाज में किसी भी प्रकार की तानाशाही या अंधविश्वास के लिए कोई स्थान नहीं बचता। यह दर्शन व्यक्ति की संप्रभुता को सर्वोच्च मानता है और उसे सभी सामूहिक पहचानों के बंधनों से मुक्त करके उसकी गरिमा को पुनर्जीवित करता है।

292. (D) यह पहचान को आकार देने में स्व की सामाजिक प्रकृति को स्वीकार करने में विफल रहता है।
समुदायवादी विचारक जॉन रॉल्स के उदारवादी न्याय सिद्धांत की तीखी आलोचना करते हैं। उनका मुख्य तर्क यह है कि रॉल्स व्यक्ति को एक 'असंलग्न स्व' के रूप में देखते हैं जो अपने सामाजिक संबंधों से अलग होकर निर्णय ले सकता है। समुदायवादियों के अनुसार, हमारी पहचान हमारे परिवार, संस्कृति और समुदाय के साझा मूल्यों से इतनी गहराई से जुड़ी होती है कि हम उनसे पूरी तरह अलग नहीं हो सकते। इसलिए न्याय की चर्चा हमेशा सामाजिक संदर्भों और साझा भलाई के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए। यह दृष्टिकोण व्यक्ति को समाज का एक अभिन्न अंग मानता है और अधिकारों के बजाय साझा उत्तरदायित्वों पर अधिक बल देता है।

293. (C) प्लेटो
प्लेटो के राजनीतिक दर्शन का शिखर 'दार्शनिक राजा' की अवधारणा है। उनका मानना था कि राज्य की समस्याओं का एकमात्र समाधान यह है कि सत्ता केवल उन लोगों के हाथ में हो जिन्होंने कठोर शिक्षा के माध्यम से पूर्ण सत्य और 'शुभ के विचार' का ज्ञान प्राप्त किया है। एक दार्शनिक राजा स्वार्थ, संपत्ति और परिवार के मोह से पूरी तरह मुक्त होता है और केवल राज्य के सामान्य कल्याण के लिए विवेकपूर्ण निर्णय लेता है। प्लेटो के अनुसार शासन एक कला और विज्ञान है जिसे केवल प्रबुद्ध बुद्धिजीवी ही सफलतापूर्वक चला सकते हैं। यह

Downloaded from www.pdf.tube

व्यवस्था राज्य में न्याय और सद्भाव सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई थी ताकि समाज में व्यवस्था बनी रहे।

294. (B) एक 'नाइट-वॉचमैन' के रूप में कार्य करना, व्यक्तियों को बल, चोरी और धोखाधड़ी से बचाना।
रॉबर्ट नोजिक एक प्रखर उदारतावादी थे जिन्होंने न्यूनतम राज्य का सशक्त बचाव किया। उनके अनुसार राज्य को केवल सुरक्षा और न्याय प्रदान करने तक ही सीमित रहना चाहिए। नोजिक का तर्क था कि यदि राज्य आर्थिक समानता लाने के लिए धनी लोगों पर भारी कर लगाता है, तो वह उनके मौलिक संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन करता है। राज्य को नागरिकों के निजी जीवन या बाजार की स्वतंत्र गतिविधियों में तब तक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जब तक कि वहां किसी के अधिकारों का हनन न हो रहा हो। यह विचार व्यक्तिगत स्वायत्तता को सर्वोच्च मानता है और राज्य के अनावश्यक विस्तार को व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए खतरा मानता है।

295. (D) लेनिन ने शहरी सर्वहारा वर्ग पर ध्यान केंद्रित किया, जबकि माओ ने किसान वर्ग पर बल दिया।
लेनिन के नेतृत्व में रूसी क्रांति मुख्य रूप से औद्योगिक केंद्रों और शहरी श्रमिकों के संगठित विद्रोह पर आधारित थी। इसके विपरीत, माओ जेदोंग ने चीन की कृषि प्रधान स्थितियों को देखते हुए किसानों को मुख्य क्रांतिकारी शक्ति माना। माओ ने 'दीर्घकालिक जनयुद्ध' की रणनीति अपनाई जिसमें गाँवों को मुक्त कराकर शहरों को चारों ओर से घेरने की योजना थी। यह रणनीतिक अंतर मार्क्सवाद के स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार रूपांतरण का एक उत्कृष्ट उदाहरण है जिसने एशियाई क्रांतियों के स्वरूप और सफलता को पूरी तरह बदल दिया। यह दर्शाता है कि विचारधारा का प्रयोग ठोस सामाजिक धरातल और संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार ही किया जाना चाहिए।

296. (A) समुदायवाद और हेगेलवाद
"मेरा स्थान और उसके कर्तव्य" का विचार व्यक्ति की पहचान को समाज में उसकी विशिष्ट भूमिका और उत्तरदायित्वों से जोड़ता है। यह दृष्टिकोण इस बात पर बल देता है कि नैतिकता और अधिकार शून्य में नहीं होते, बल्कि वे उस सामाजिक ढांचे और समुदाय का हिस्सा हैं जिसमें हम रहते हैं। यह हेगेल के 'नैतिक जीवन' और समुदायवादी दर्शन से मेल खाता है, जहाँ व्यक्ति की सार्थकता उसके सामाजिक संबंधों और सार्वजनिक हित के प्रति उसके योगदान में ही निहित मानी जाती है। यह विचार व्यक्ति को एक सामाजिक इकाई के रूप में देखता है जिसके अधिकार उसके कर्तव्यों से बंधे होते हैं और जो समुदाय की प्रगति के लिए अनिवार्य अंग माना गया है।

297. (C) सुख और दुख
जेरेमी बेंथम के उपयोगितावाद का केंद्र मानवीय संवेदनाएं हैं। उनके अनुसार प्रकृति ने मनुष्य को दो संप्रभु स्वामियों—सुख और दुख—के अधीन रखा है। किसी भी कार्य की उपयोगिता और नैतिकता केवल इस बात से तय होती है कि वह सुख में कितनी वृद्धि करता है और दुख को कितना कम करता है। बेंथम ने नीतियों का मूल्यांकन करने के लिए एक मात्रात्मक पैमाना दिया जिसका उद्देश्य 'अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख' सुनिश्चित करना था। यह सिद्धांत कानूनों को धार्मिक मान्यताओं के बजाय मानवीय परिणामों पर आधारित करता है, जिससे शासन व्यवस्था को एक व्यावहारिक और जन-केंद्रित आधार प्राप्त होता है। यह विधिशास्त्र में एक बड़ा सुधारवादी कदम था।

298. (A) शुभ पर अधिकार को।
जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत की एक प्रमुख विशेषता यह है कि वे 'अधिकार' को 'शुभ' की किसी भी विशिष्ट अवधारणा से ऊपर रखते हैं। इसका अर्थ है कि एक न्यायपूर्ण समाज में कानून और नीतियां किसी एक धर्म या जीवनशैली के अनुसार नहीं होनी चाहिए, बल्कि वे उन निष्पक्ष नियमों पर आधारित होनी चाहिए जो सभी को समान अधिकार और स्वतंत्रता दें। रॉल्स का मानना था कि लोग अपनी पसंद के अनुसार अपने जीवन के लक्ष्यों की खोज कर सकें, इसके लिए राज्य का ढांचा केवल तटस्थ और न्यायपूर्ण अधिकारों पर आधारित होना चाहिए। यह विविधतापूर्ण समाजों में स्थिरता और शांति सुनिश्चित करने का एक ठोस और तर्कसंगत उदारवादी मार्ग है।

299. (A) केवल 1 और 2
एंटोनियो ग्राम्शी ने 'जैविक बुद्धिजीवी' की अवधारणा दी जो अपने वर्ग के हितों को वैचारिक दिशा प्रदान करते हैं। रॉबर्ट नोजिक ने 'न्यूनतम राज्य' का समर्थन किया जो केवल व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करता है और बाजार में हस्तक्षेप नहीं करता। हालांकि, 'सामान्य इच्छा' का विचार ज्यां-जैक रूसो से जुड़ा है, न कि टी.एच. ग्रीन से। ग्रीन मुख्य रूप से 'सकारात्मक स्वतंत्रता' और 'सामान्य हित' की बात करते हैं जो नैतिकता पर आधारित है। अतः प्रथम दो युग्म सही सुमेलित हैं जबकि तीसरा राजनीतिक चिंतन के इतिहास में एक अलग विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता है। यह मिलान महत्वपूर्ण अवधारणाओं को स्पष्ट करने में सहायक है।

300. (B) जॉन स्टुअर्ट मिल
जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'महिलाओं की अधीनता' में महिलाओं की पराधीनता के विरुद्ध सशक्त दलीलें पेश कीं। उन्होंने तर्क दिया कि महिलाओं को समाज में पुरुषों के समान कानूनी और राजनीतिक अधिकार न देना सरासर अन्यायपूर्ण है और यह पूरी मानवता की प्रगति में एक बड़ी बाधा है। मिल ने विवाह संस्था में सुधार, शिक्षा और रोजगार में पूर्ण समानता की मांग की। यह कृति उदारवादी नारीवाद के इतिहास में एक मील का पत्थर मानी जाती है क्योंकि इसने समानता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के सिद्धांतों को महिलाओं के संदर्भ में विस्तार दिया और एक न्यायपूर्ण समाज की नींव रखने का प्रयास किया।

NODIA
www.nodia.in

अध्याय 02
राजनीतिक अवधारणाएँ एवं मुद्दे

1. चर्च-राज्य संबंधों पर मध्यकालीन बहस में कौन सी अवधारणा केंद्रीय है?
(A) लोकप्रिय संप्रभुता
(B) दो तलवारों का सिद्धांत
(C) राजाओं का दैवीय अधिकार
(D) शक्तियों का पृथक्करण

2. राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद के संबंध में सही कथन की पहचान कीजिए।
(A) यह व्यक्तियों के प्रत्यक्ष कार्यों के माध्यम से राजनीतिक गतिविधि की व्याख्या करता है।
(B) यह ऐतिहासिक वृत्तांतों और दार्शनिक ग्रंथों पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करता है।
(C) यह औपचारिक संस्थानों और कानूनी संरचनाओं के विश्लेषण को प्राथमिकता देता है।
(D) यह मानकीय प्रश्नों और मूल्यों की खोज पर जोर देता है।

3. दिए गए दो कथनों पर विचार करें और सही उत्तर चुनें:
कथन I: प्रक्रियात्मक लोकतंत्र शासन के तंत्र और प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करता है, जैसे कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव।
कथन II: सारवान लोकतंत्र वास्तविक परिणामों और उस सीमा से संबंधित है जिस तक समानता और न्याय प्राप्त किया गया है।
(A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं।
(C) कथन I सत्य है, लेकिन कथन II असत्य है।
(D) कथन I असत्य है, लेकिन कथन II सत्य है।

4. "नकारात्मक स्वतंत्रता" की सबसे सटीक परिभाषा क्या है?
(A) उस तरीके से कार्य करने की क्षमता जिससे व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को साकार कर सके।
(B) किसी समुदाय या राष्ट्र द्वारा प्राप्त सामूहिक स्वतंत्रता।
(C) अतार्किक इच्छाओं और भयों से आंतरिक मुक्ति।
(D) बाहरी बाधाओं या दूसरों द्वारा हस्तक्षेप से मुक्ति।

5. सिद्धांतकार को उनके परिवर्तन की प्राथमिक अवधारणा के साथ सुमेलित करें।
सूची I: (सिद्धांतकार)
P. लेनिन
Q. माओ
R. गांधी
S. कार्ल मार्क्स
सूची II: (परिवर्तन की अवधारणा)
1. लंबी अवधि का जनयुद्ध
2. सत्याग्रह
3. सर्वहारा की तानाशाही
4. अग्रगामी दल
(A) P-4, Q-1, R-2, S-3
(B) P-3, Q-2, R-1, S-4
(C) P-4, Q-3, R-2, S-1
(D) P-1, Q-4, R-3, S-2

6. एक सरकार कानून पारित करती है कि सभी सार्वजनिक भवन दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभ होने चाहिए। यह कार्रवाई किस अवधारणा का प्रत्यक्ष अनुप्रयोग है?
(A) व्यक्तिगत न्याय
(B) सामाजिक न्याय
(C) प्रक्रियात्मक स्वतंत्रता
(D) नकारात्मक स्वतंत्रता

7. राजनीति विज्ञान में व्यवहारवादी दृष्टिकोण की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है?
(A) अवलोकनीय और मात्रात्मक डेटा पर ध्यान केंद्रित करना।
(B) तथ्यात्मक डेटा को नैतिक मूल्यों से अलग करना।
(C) राजनीति विज्ञान का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ एकीकरण।
(D) मानकीय और दार्शनिक जांच की प्रधानता।

8. मध्यकाल में प्रतिपादित "दो तलवारों का सिद्धांत" मुख्य रूप से किन दो संस्थाओं के बीच अधिकार के विभाजन से संबंधित था?
(A) पोपतंत्र और राजतंत्र
(B) सम्राट और सीनेट
(C) सामंत और जागीरदार
(D) कुलीन वर्ग और किसान वर्ग

9. "अवसर की समानता" की अवधारणा को सबसे अच्छी तरह इस प्रकार वर्णित किया गया है:
(A) यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक नागरिक समान स्तर की संपत्ति प्राप्त करे।
(B) आवश्यकता की परवाह किए बिना व्यक्तियों को समान संसाधन प्रदान करना।
(C) कृत्रिम बाधाओं को दूर करना ताकि सभी को समान अवसर मिल सके।
(D) यह गारंटी देना कि सभी आर्थिक असमानताएँ पूरी तरह

Click Here to Buy book on Amazon

समाप्त हो जाएँगी।

10. निम्नलिखित अभिकथन (A) और कारण (R) पर विचार करें।
अभिकथन (A): उत्तर-व्यवहारवाद व्यवहारवादी क्रांति की कथित अतिशयोक्तियों के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया थी।
कारण (R): उत्तर-व्यवहारवादियों ने तर्क दिया कि शोध को दबावपूर्ण सामाजिक मुद्दों के लिए प्रासंगिक होना चाहिए और मूल्यों की उपेक्षा नहीं की जा सकती।
(A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(D) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

11. लेनिन के परिवर्तन के सिद्धांत के अनुसार, "अग्रगामी दल" की प्राथमिक भूमिका क्या है?
(A) विधायिका में बुर्जुआ वर्ग के हितों का प्रतिनिधित्व करना।
(B) व्यवस्था के भीतर क्रमिक, शांतिपूर्ण सुधारों की वकालत करना।
(C) प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित करना जहाँ सभी नागरिक भाग लें।
(D) राज्य के विरुद्ध क्रांति में सर्वहारा वर्ग का नेतृत्व करना।

12. न्याय की अवधारणाओं के संबंध में गलत युग्म की पहचान करें।
(A) सामाजिक न्याय - संसाधनों का उचित वितरण
(B) प्रक्रियात्मक न्याय - परिणामों पर प्राथमिक ध्यान
(C) व्यक्तिगत न्याय - कानून की उचित प्रक्रिया
(D) वितरणात्मक न्याय - सामाजिक निष्पक्षता से संबंधित

13. 20वीं शताब्दी के मध्य में "राजनीतिक सिद्धांत के पतन" का कारण कुछ विद्वानों ने किन दो आंदोलनों के उदय को माना था?
(A) आदर्शवाद और यथार्थवाद
(B) मार्क्सवाद और अराजकतावाद
(C) इतिहासवाद और प्रत्यक्षवाद
(D) परंपरावाद और औपचारिकतावाद

14. दिए गए दो कथनों पर विचार करें और सही उत्तर चुनें:
कथन I: नकारात्मक स्वतंत्रता और परिणामों की समानता को अक्सर पूरक लक्ष्यों के रूप में देखा जाता है।
कथन II: सकारात्मक स्वतंत्रता के लिए अक्सर राज्य के हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है, जिसे नकारात्मक स्वतंत्रता के लिए खतरे के रूप में देखा जा सकता है।
(A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं।
(C) कथन I सत्य है, लेकिन कथन II असत्य है।
(D) कथन I असत्य है, लेकिन कथन II सत्य है।

15. मध्यकालीन राजनीतिक चिंतन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
I. चर्च ने आध्यात्मिक अधिकार का दावा किया, जबकि राज्य के पास लौकिक अधिकार था।
II. "दो तलवारों के सिद्धांत" ने बिना किसी अतिव्याप्ति के स्पष्ट पृथक्करण का प्रस्ताव दिया।
III. सर्वोच्चता को लेकर विवादों के कारण संबंध अक्सर विवादास्पद रहे।
उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) केवल I
(B) केवल I और III
(C) केवल II और III
(D) I, II और III

16. राजनीति विज्ञान में उत्तर-व्यवहारवाद का सबसे महत्वपूर्ण योगदान क्या है?
(A) अनुभवजन्य और वैज्ञानिक पद्धतियों को पूर्णतः अस्वीकार करना।
(B) मूल्यों और प्रासंगिकता के महत्व पर ध्यान केंद्रित करना।
(C) विशेष रूप से मात्रात्मक डेटा विश्लेषण पर एकाग्रता।
(D) सिद्धांत को व्यवहार से अलग करने का तर्क।

17. माओ का परिवर्तन का सिद्धांत, विशेष रूप से "लंबी अवधि का जनयुद्ध," किस प्रकार के समाज के लिए सबसे अधिक लागू होता है?
(A) एक उन्नत औद्योगिक पूंजीवादी समाज।
(B) किसान बहुसंख्यक वाला एक बड़ा कृषि प्रधान समाज।
(C) एक स्थिर, बहुदलीय उदार लोकतंत्र।
(D) एक छोटा, शहरीकृत नगर-राज्य।

18. न्याय के संदर्भ में, "प्रक्रियात्मक न्याय" मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?
(A) संसाधनों के आवंटन के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाओं की निष्पक्षता।
(B) यह सुनिश्चित करना कि वस्तुओं का अंतिम वितरण न्यायसंगत हो।
(C) सकारात्मक कार्रवाई के माध्यम से ऐतिहासिक अन्यायों को सुधारना।
(D) अधिकतम संख्या के लिए अधिकतम भलाई प्राप्त करना।

19. निम्नलिखित में से कौन सी प्रत्यक्ष लोकतंत्र की एक सामान्य आलोचना है?
(A) यह निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथों में बहुत अधिक शक्ति केंद्रित करता है।
(B) यह नागरिक भागीदारी के लिए तंत्र प्रदान करने में विफल रहता है।
(C) जटिल समाजों के शासन के लिए यह अक्सर बहुत धीमा होता है।
(D) यह स्वाभाविक रूप से अभिजात्यवादी और बहिष्कारी है।

NODIA

20. अवधारणा को उसके उपयुक्त विवरण के साथ सुमेलित करें।
सूची I: (अवधारणा)
P. सकारात्मक स्वतंत्रता
Q. सामाजिक न्याय
R. व्यवहारवाद
S. दो तलवारों का सिद्धांत
सूची II: (विवरण)
1. राजनीति का अनुभवजन्य अध्ययन
2. आत्म-साक्षात्कार
3. अधिकार का विभाजन
4. उचित वितरण
(A) P-1, Q-3, R-4, S-2
(B) P-2, Q-4, R-1, S-3
(C) P-3, Q-1, R-2, S-4
(D) P-2, Q-4, R-3, S-1

21. गांधीवादी परिवर्तन का सिद्धांत मौलिक रूप से किस सिद्धांत पर आधारित है?
(A) दमनकारी शासन को हिंसक रुप से उखाड़ फेंकना।
(B) एक क्रांतिकारी अग्रगामी दल द्वारा राज्य सत्ता पर कब्जा।
(C) अहिंसा के माध्यम से नैतिक परिवर्तन।
(D) राजनीतिक अभिजात वर्ग द्वारा क्रमिक विधायी सुधार।

22. व्यवहारवादी दृष्टिकोण का एक प्रमुख सिद्धांत राजनीतिक व्यवहार में "नियमितताओं" की खोज था। इसका क्या तात्पर्य है?
(A) राजनीतिक घटनाएँ अनूठी होती हैं और उनकी तुलना नहीं की जा सकती।
(B) राजनीतिक व्यवहार में खोजे जाने योग्य एकरूपताएँ मौजूद हैं।
(C) मानवीय राजनीतिक क्रियाएँ यादृच्छिक और अप्रत्याशित हैं।
(D) एकमात्र नियमितता अभिजात वर्ग द्वारा सत्ता की खोज है।

23. मध्यकाल में प्रतिपादित "दो तलवारों का सिद्धांत" किस ऐतिहासिक व्यक्तित्व के पत्र से उत्पन्न हुआ था?
(A) सेंट ऑगस्टीन
(B) सम्राट कॉन्सटेंटाइन
(C) थॉमस एक्विनास
(D) पोप जेलासियस I

24. एक राजनीतिक व्यवस्था जो नियमित चुनाव कराती है लेकिन विपक्षी दलों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दमन करती है, उसे सबसे सटीक रूप से किसका अभाव बताया जा सकता है:
(A) सारवान लोकतंत्र
(B) प्रक्रियात्मक लोकतंत्र
(C) एक औपचारिक संविधान
(D) राजशाही व्यवस्था

25. निम्नलिखित अभिकथन (A) और कारण (R) पर consider करें।
अभिकथन (A): गांधी की सत्याग्रह की अवधारणा केवल एक राजनीतिक उपकरण नहीं बल्कि जीवन का एक व्यापक दर्शन है।
कारण (R): सत्याग्रह में सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन प्राप्त करने के लिए सत्य के प्रति आग्रह और अहिंसक शक्ति पर भरोसा शामिल है।
(A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(D) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

26. कौन सा कथन उत्तर-व्यवहारवाद के "प्रासंगिकता और कार्रवाई" के नारे का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है?
(A) वैज्ञानिकों को सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए ज्ञान का प्रयोग करना चाहिए।
(B) विज्ञान को सामाजिक समस्याओं से अलग होना चाहिए।
(C) शोध को तकनीकी परिष्कार को प्राथमिकता देनी चाहिए।
(D) कार्रवाई का अर्थ केवल मूल्य-मुक्त डेटा का संचय है।

27. "कानून के समक्ष समानता" की अवधारणा किस प्रकार के न्याय की आधारशिला है?
(A) सामाजिक न्याय
(B) वितरणात्मक न्याय
(C) आर्थिक न्याय
(D) व्यक्तिगत न्याय

28. चर्च-राज्य बहस में, यह तर्क कि आध्यात्मिक तलवार लौकिक तलवार से श्रेष्ठ थी, किसका औचित्य सिद्ध करने के लिए उपयोग किया गया था?
(A) सम्राट की पूर्ण शक्ति।
(B) धर्मनिरपेक्ष शासकों पर पोप की सर्वोच्चता।
(C) चर्च और राज्य का पूर्ण पृथक्करण और समानता।
(D) समाज में चर्च की भूमिका का उन्मूलन।

29. लेनिन के अनुसार, "पूंजीवाद की सर्वोच्च अवस्था" क्या थी?
(A) व्यापारवाद
(B) मुक्त बाजार प्रतिस्पर्धा
(C) साम्राज्यवाद
(D) सामाजिक लोकतंत्र

30. राजनीति विज्ञान में निम्नलिखित विचारधाराओं को उनके उदय के कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें:
1. उत्तर-व्यवहारवाद
2. परंपरावाद
3. व्यवहारवाद
(A) 1, 2, 3
(B) 2, 3, 1

Downloaded from www.pdf.tube

(C) 3, 1, 2
(D) 2, 1, 3

31. एक कानून जो गरीबों के लिए सामाजिक कार्यक्रमों को निधि देने हेतु धनवानों पर उच्च कर लगाता है, वह राज्य द्वारा किसे बढ़ावा देने का एक उदाहरण है?
(A) परिणाम की समानता
(B) नकारात्मक स्वतंत्रता
(C) अवसर की समानता
(D) प्रक्रियात्मक न्याय

32. "राजनीतिक सिद्धांत का पुनरुत्थान" अक्सर उन विचारकों के कार्यों से जुड़ा होता है जो निम्नलिखित में से किसके साथ पुनः जुड़े?
(A) मात्रात्मक डेटा विश्लेषण और सांख्यिकीय मॉडलिंग।
(B) महान दार्शनिक और मानकीय प्रश्न।
(C) मतदान व्यवहार और विधायी प्रक्रियाओं का अध्ययन।
(D) प्रणाली विश्लेषण और साइबरनेटिक्स।

33. निम्नलिखित में से कौन सा गांधी की सत्याग्रह पद्धति का घटक नहीं है?
(A) सविनय अवज्ञा
(B) असहयोग
(C) अंतिम उपाय के रूप में रणनीतिक हिंसा
(D) उपवास

34. दिए गए दो कथनों पर विचार करें और सही उत्तर चुनें:
कथन I: व्यवहारवाद की अक्सर इसके "तथ्य-मूल्य द्विभाजन" के लिए आलोचना की जाती है, जो अनुभवजन्य तथ्यों को मानकीय मूल्यों से अलग करने पर जोर देता है।
कथन II: उत्तर-व्यवहारवाद ने इस द्विभाजन को खारिज कर दिया, यह तर्क देते हुए कि राजनीतिक विश्लेषण में तथ्य और मूल्य अटूट रूप से जुड़े हुए हैं।
(A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं।
(C) कथन I सत्य है, लेकिन कथन II असत्य है।
(D) कथन I असत्य है, लेकिन कथन II सत्य है।

35. विचारधारा की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
I. विचारधारा राजनीतिक दुनिया को समझने और व्याख्या करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है।
II. सभी विचारधाराएँ स्वाभाविक रूप से क्रांतिकारी होती हैं और मौजूदा व्यवस्था को उखाड़ फेंकना चाहती हैं।
III. विचारधारा सामूहिक राजनीतिक कार्रवाई के लिए व्यक्तियों और समूहों को लामबंद कर सकती है।
उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) केवल I और II
(B) केवल I और III
(C) केवल II
(D) I, II और III

36. माओ के क्रांति के सिद्धांत में वह केंद्रीय विचार क्या है जो इसे शास्त्रीय मार्क्सवाद-लेनिनवाद से अलग करता है?
(A) औद्योगिक सर्वहारा वर्ग को मुख्य क्रांतिकारी वर्ग मानना।
(B) शांतिपूर्ण माध्यमों से समाजवाद की प्राप्ति।
(C) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों का महत्व।
(D) किसानों को प्राथमिक क्रांतिकारी शक्ति मानना।

37. मध्यकालीन यूरोप के संदर्भ में, "लौकिक शक्ति" का क्या अर्थ है?
(A) आध्यात्मिक मामलों पर चर्च का अधिकार।
(B) सांसारिक, धर्मनिरपेक्ष मामलों से संबंधित शक्ति।
(C) विश्वविद्यालयों का बौद्धिक अधिकार।
(D) व्यापारिक श्रेणियों की आर्थिक शक्ति।

NODIA

38. "एक व्यक्ति, एक वोट" का सिद्धांत किस अवधारणा का मौलिक पहलू है?
(A) सकारात्मक स्वतंत्रता
(B) सामाजिक न्याय
(C) राजनीतिक समानता
(D) आर्थिक समानता

39. यह आलोचना कि राजनीतिक सिद्धांत "पतित" हो गया था क्योंकि इसने अपनी महान, मानकीय परंपरा को छोड़ दिया था, सबसे निकटता से किससे जुड़ी है?
(A) व्यवहारवादी
(B) उत्तर-व्यवहारवादी
(C) स्ट्रॉसियन दृष्टिकोण
(D) मार्क्सवादी

40. सिद्धांतकार को राज्य पर उनके दृष्टिकोण के साथ सुमेलित करें।
सूची I: (सिद्धांतकार)
P. गांधी
Q. लेनिन
R. माओ
S. जॉन लॉक
सूची II: (राज्य पर दृष्टिकोण)
1. वर्ग उत्पीड़न का उपकरण
2. जनता की तानाशाही
3. हिंसक संस्था
4. सामाजिक अनुबंध निकाय
(A) P-3, Q-1, R-2, S-4
(B) P-1, Q-2, R-3, S-4
(C) P-3, Q-4, R-1, S-2
(D) P-4, Q-1, R-2, S-3

41. "सामाजिक न्याय" का सबसे उपयुक्त वर्णन क्या है?
(A) बिना किसी अपवाद के लिखित कानूनों का सख्ती से पालन।
(B) व्यक्तिगत अधिकारों और हस्तक्षेप से मुक्ति पर ध्यान

केंद्रित करना।
(C) संसाधनों और अवसरों का उचित वितरण।
(D) प्रतिशोध के सिद्धांतों के आधार पर अपराधियों को दंड देना।

42. उत्तर-व्यवहारवाद के बारे में गलत कथन की पहचान करें।
(A) इसने भविष्योन्मुखी "रचनात्मक सिद्धांत" का आह्वान किया।
(B) इसने तर्क दिया कि तकनीक को विषय-वस्तु से अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए।
(C) यह शुद्ध, अवैज्ञानिक परंपरावाद की ओर वापसी थी।
(D) इसने समाज में वैज्ञानिक की भूमिका पर जोर दिया।

43. मध्यकालीन चिंतन में, यह विचार कि ईश्वर ने एक तलवार पोप को और दूसरी सम्राट को दी थी, किसका सरलीकृत प्रतिनिधित्व है?
(A) ऑगस्टिनियन द्वैतवाद
(B) राजाओं का दैवीय अधिकार
(C) जेलासियन सिद्धांत
(D) सामंती अनुबंध सिद्धांत

44. निम्नलिखित में से कौन सा परिदृश्य "सकारात्मक स्वतंत्रता" की अवधारणा को सबसे अच्छी तरह से स्पष्ट करता है?
(A) एक व्यक्ति को वह सब कुछ करने के लिए अकेला छोड़ दिया जाता है जो वह चाहता है।
(B) एक कानून रद्द कर दिया जाता है, जिससे एक विशिष्ट प्रतिबंध हट जाता है।
(C) एक व्यक्ति दूसरों से अलग-थलग रहने का विकल्प चुनता है।
(D) एक सरकार नागरिकों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षा प्रदान करती है।

45. निम्नलिखित अभिकथन (A) और कारण (R) पर विचार करें।
अभिकथन (A): राजनीति विज्ञान में व्यवहारवादी क्रांति ने अनुशासन को अधिक वैज्ञानिक बनाने की मांग की।
कारण (R): व्यवहारवादियों ने अनुभवजन्य विधियों, परिमाणीकरण और अवलोकनीय डेटा के आधार पर परिकल्पनाओं के सत्यापन की वकालत की।
(A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(D) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

46. माओ द्वारा शुरू की गई "सांस्कृतिक क्रांति" का उद्देश्य क्या था?
(A) अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पारंपरिक चीनी कलाओं को बढ़ावा देना।
(B) चीनी समाज से पूंजीवादी तत्वों को बाहर निकालना।
(C) विदेशी निवेश के लिए चीन की अर्थव्यवस्था को खोलना।
(D) एक बहुदलीय लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करना।

47. सही युग्म की पहचान करें।
(A) लेनिन - लंबी अवधि का जनयुद्ध
(B) माओ - अग्रगामी दल
(C) असहयोग - गांधी
(D) मार्क्स - दो तलवारों का सिद्धांत

48. राजनीतिक सिद्धांत के कथित "पतन" के बाद इसके "पुनरुत्थान" की विशेषता क्या थी?
(A) रॉल्स और नोज़िक जैसे विचारकों के महत्व का नवीनीकरण।
(B) सभी अनुभवजन्य शोधों का पूर्ण परित्याग।
(C) मानक के रूप में व्यवहारवाद की सार्वभौमिक स्वीकृति।
(D) विशेष रूप से मध्यकालीन राजनीतिक संस्थानों पर ध्यान केंद्रित करना।

49. न्याय की कौन सी अवधारणा समाज के सदस्यों, विशेष रूप से वंचितों के लिए "समान अवसर प्रदान करने" से सबसे अधिक संबंधित है?
(A) प्रतिशोधक न्याय
(B) प्रक्रियात्मक न्याय
(C) सामाजिक न्याय
(D) विनिमय न्याय

50. मध्यकालीन चर्च-राज्य संबंधों में मुख्य तनाव किस प्रश्न पर था?
(A) आर्थिक नीति
(B) अंतिम संप्रभुता
(C) सैन्य रणनीति
(D) शैक्षिक पाठ्यक्रम

51. दिए गए दो कथनों पर विचार करें और सही उत्तर चुनें:
कथन I: लेनिन का मानना था कि सर्वहारा वर्ग अपने दम पर केवल "ट्रेड-यूनियन चेतना" विकसित कर सकता है, क्रांतिकारी चेतना नहीं।
कथन II: उन्होंने तर्क दिया कि श्रमिकों का मार्गदर्शन करने के लिए पेशेवर क्रांतिकारियों के एक अनुशासित दल की आवश्यकता थी।
(A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं।
(C) कथन I सत्य है, लेकिन कथन II असत्य है।
(D) कथन I असत्य है, लेकिन कथन II सत्य है।

52. राजनीति विज्ञान में "विचारधारा" शब्द को सबसे अच्छी तरह इस प्रकार समझा जा सकता है:
(A) दूसरों को गुमराह करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले झूठे विश्वासों का एक समूह।
(B) विचारों का एक सुसंगत समूह जो कार्रवाई के लिए कार्यक्रम प्रदान करता है।
(C) बिना किसी व्यावहारिक अनुप्रयोग वाली एक विशुद्ध

Click Here to Buy book on Amazon

दार्शनिक प्रणाली।
(D) किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत, अपरीक्षित राय।

53. व्यवहारवाद और उत्तर-व्यवहारवाद के बीच एक प्रमुख अंतर निम्नलिखित में से किसके प्रति उनके दृष्टिकोण में निहित है?
(A) राज्य
(B) चुनावों का महत्व
(C) शोध में मूल्यों की भूमिका
(D) विधायिका की संरचना

54. एक प्रतिनिधि लोकतंत्र का आदर्श यह है कि:
(A) सभी नागरिक प्रत्येक कानून और नीति पर मतदान करते हैं।
(B) एक एकल, प्रबुद्ध नेता सार्वजनिक भलाई के लिए शासन करता है।
(C) राजनीतिक शक्ति राजशाही की व्यवस्था के माध्यम से विरासत में मिलती है।
(D) लोग उनके लिए निर्णय लेने हेतु अधिकारियों का चुनाव करते हैं।

55. परिवर्तन के प्रति गांधी के दृष्टिकोण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
I. इसने साध्य की प्राप्ति पर साधनों की शुद्धता को प्राथमिकता दी।
II. इसने राज्य को सभी सामाजिक समस्याओं के अंतिम समाधान के रूप में देखा।
III. इसने व्यक्तिगत नैतिक जिम्मेदारी और आत्म-परिवर्तन पर जोर दिया।
उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) केवल I
(B) केवल I और III
(C) केवल II और III
(D) I, II और III

56. 1950 के दशक में किस विद्वान ने "राजनीतिक सिद्धांत के पतन" की प्रसिद्ध घोषणा की थी?
(A) लियो स्ट्रॉस
(B) डेविड ईस्टन
(C) हन्ना आरेंड्ट
(D) शेल्डन वोलिन

57. माओवादी दृष्टिकोण से, एक अर्ध-औपनिवेशिक देश में क्रांति की शुरुआत होनी चाहिए:
(A) प्रमुख औद्योगिक शहरों में हड़तालें आयोजित करके।
(B) साम्राज्यवादी शक्तियों के साथ गठबंधन करके।
(C) बुर्जुआ संसदीय चुनावों में भाग लेकर।
(D) ग्रामीण इलाकों में आधार क्षेत्र स्थापित करके।

58. निम्नलिखित में से कौन सा दो तलवारों के सिद्धांत में निहित संघर्ष को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है?
(A) पोप और सम्राट के बीच पदनियुक्ति विवाद।
(B) कानून के मामले में एक राजा का बिशप से परामर्श करना।
(C) एक भिक्षु द्वारा शास्त्रीय दार्शनिक ग्रंथ का अनुवाद करना।
(D) एक सामंत द्वारा अपने जागीरदार को जागीर देना।

59. सकारात्मक कार्रवाई नीतियां किस अवधारणा से सबसे निकटता से जुड़ी हैं?
(A) नकारात्मक स्वतंत्रता
(B) केवल योग्यता पर आधारित व्यक्तिगत न्याय
(C) ऐतिहासिक नुकसान के लिए सामाजिक न्याय
(D) राज्य और समाज का पूर्ण पृथक्करण

60. राजनीतिक अवधारणा को उसके सबसे प्रासंगिक मुख्य शब्द के साथ सुमेलित करें।
सूची I: (अवधारणा)
P. व्यवहारवाद
Q. उत्तर-व्यवहारवाद
R. नकारात्मक स्वतंत्रता
S. सकारात्मक स्वतंत्रता
सूची II: (मुख्य शब्द)
1. आत्म-प्रभुत्व
2. बाधा का अभाव
3. प्रासंगिकता
4. सत्यापन
(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-4, Q-3, R-1, S-2
(C) P-4, Q-3, R-2, S-1
(D) P-3, Q-4, R-2, S-1

61. निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक समानता का प्रयोग करने का एक उदाहरण है?
(A) प्रदर्शन के आधार पर पदोन्नति प्राप्त करना।
(B) आम चुनाव में वोट डालना।
(C) सार्वजनिक कंपनी में शेयर खरीदना।
(D) बड़ी राशि विरासत में प्राप्त करना।

62. उत्तर-व्यवहारवादी "प्रासंगिकता के सिद्धांत" का तात्पर्य था कि:
(A) शोध का मूल्यांकन केवल पद्धतिगत कठोरता के आधार पर किया जाना चाहिए।
(B) वैज्ञानिकों को समाज के तटस्थ पर्यवेक्षक बने रहना चाहिए।
(C) शोध प्राथमिकताओं को सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए।
(D) शास्त्रीय ग्रंथों का अध्ययन राजनीति के लिए अप्रासंगिक है।

63. "सर्वहारा की तानाशाही" की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तावित परिवर्तन के सिद्धांत में केंद्रीय है?
(A) गांधी

Downloaded from www.pdf.tube

(B) माओ
(C) लेनिन
(D) जॉन स्टुअर्ट मिल

64. व्यक्तिगत और सामाजिक न्याय के बीच मौलिक अंतर क्या है?
(A) व्यक्तिगत न्याय आपराधिक है; सामाजिक न्याय दीवानी है।
(B) व्यक्तिगत न्याय लेनदेन संबंधी है; सामाजिक न्याय संरचनात्मक है।
(C) व्यक्तिगत न्याय आधुनिक है; सामाजिक न्याय प्राचीन है।
(D) कोई अंतर नहीं है; ये शब्द एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किए जा सकते हैं।

65. निम्नलिखित अभिकथन (A) और कारण (R) पर विचार करें।
अभिकथन (A): मध्यकालीन राजनीतिक व्यवस्था खंडित और अतिव्यापी अधिकारों द्वारा चिह्नित थी।
कारण (R): साम्राज्य और पोपतंत्र के सार्वभौमिक दावों के साथ सामंती प्रभुओं की स्थानीय शक्ति मौजूद थी, जिससे अधिकार क्षेत्रों का एक जटिल जाल बन गया था।
(A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(D) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

66. यह विचार कि स्वतंत्रता वह करने में सक्षम होने में निहित है जो कोई चाहता है, बिना दूसरों द्वारा मजबूर किए या हस्तक्षेप किए, उसे कहा जाता है:
(A) सकारात्मक स्वतंत्रता
(B) नकारात्मक स्वतंत्रता
(C) सामूहिक स्वतंत्रता
(D) गणतांत्रिक स्वतंत्रता

67. लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
(A) यह एक ऐसी प्रणाली है जहाँ शक्ति जनता में निहित होती है।
(B) आधुनिक लोकतंत्र आमतौर पर प्रतिनिधि होते हैं।
(C) लोकतंत्र केवल मतदान के कार्य से संबंधित है।
(D) इसका मूल्यांकन प्रक्रियात्मक और सारवान दोनों संदर्भों में किया जा सकता है।

68. राजनीति विज्ञान के व्यवहारवादी दृष्टिकोण पर किसका भारी प्रभाव था?
(A) प्राकृतिक विज्ञान और निष्पक्षता की इच्छा।
(B) शास्त्रीय दर्शन और पाठ्य व्याख्या।
(C) ऐतिहासिक वृत्तांत और राजनयिक इतिहास।
(D) कानूनी औपचारिकता और संस्थागत विश्लेषण।

69. माओ के अनुसार, पूर्व-क्रांतिकारी चीन जैसे अर्ध-औपनिवेशिक समाज में "मुख्य अंतर्विरोध" किसके बीच था?
(A) सर्वहारा और बुर्जुआ वर्ग।
(B) राष्ट्र और साम्राज्यवाद।
(C) जमींदार और किसान।
(D) आधुनिक विचार और पारंपरिक संस्कृति।

70. दिए गए दो कथनों पर विचार करें और सही उत्तर चुनें:
कथन I: "दो तलवारों के सिद्धांत" ने चर्च और राज्य के बीच के संघर्ष को स्थायी रूप से हल कर दिया।
कथन II: इस सिद्धांत की व्याख्या पापल और शाही समर्थकों द्वारा सर्वोच्चता का दावा करने के लिए अलग-अलग तरह से की गई थी।
(A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं।
(C) कथन I सत्य है, लेकिन कथन II असत्य है।
(D) कथन I असत्य है, लेकिन कथन II सत्य है।

71. गांधीवादी अवधारणा 'सर्वोदय' का अर्थ है:
(A) सभी का कल्याण।
(B) स्व का शासन।
(C) सत्य की शक्ति।
(D) बहुमत का अत्याचार।

72. 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में राजनीतिक सिद्धांत के "पुनरुत्थान" में किस पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया गया?
(A) मतदान प्रतिमानों का सांख्यिकीय विश्लेषण।
(B) न्याय और अधिकारों के मानकीय प्रश्न।
(C) राज्य की प्रशासनिक संरचनाएं।
(D) यथार्थवादी दृष्टिकोण से अंतर्राष्ट्रीय संबंध।

73. एक सरकारी नीति जो सभी नागरिकों को सार्वभौमिक बुनियादी आय प्रदान करती है, न्याय के किस रूप को आगे बढ़ाने का प्रयास है?
(A) प्रतिशोधक न्याय
(B) प्रक्रियात्मक न्याय
(C) सामाजिक न्याय
(D) विनिमय न्याय

74. व्यवहारवाद का एक मूल विश्वास यह है कि:
(A) राजनीतिक घटनाओं का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन नहीं किया जा सकता।
(B) राजनीतिक जांच में मूल्य और तथ्य अविभाज्य हैं।
(C) राजनीति विज्ञान को इस बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि "क्या होना चाहिए।"
(D) राजनीतिक व्यवहार में खोजने योग्य एकरूपताएँ मौजूद हैं।

75. उत्तर-व्यवहारवाद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
I. यह व्यवहारवादी आंदोलन का पूर्ण परित्याग था।

NODIA

II. इसने तर्क दिया कि राजनीति का अध्ययन मूल्य-निरपेक्ष नहीं हो सकता।
III. इसे "एक क्रांति, न कि एक प्रति-क्रांति" के रूप में वर्णित किया गया था।
उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) केवल I और II
(B) केवल II और III
(C) केवल I
(D) I, II और III

76. नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता के बीच बहस में, कौन सा विचारक इस अंतर से प्रसिद्ध रूप से जुड़ा है?
(A) जॉन रॉल्स
(B) यशायाह बर्लिन
(C) रॉबर्ट नोज़िक
(D) कार्ल मार्क्स

77. माओ की "गांवों द्वारा शहरों को घेरने" की रणनीति उनके किस विश्वास का सीधा परिणाम थी?
(A) शहरी सर्वहारा वर्ग की क्रांतिकारी क्षमता।
(B) तेजी से शहरी-आधारित तख्तापलट की आवश्यकता।
(C) क्रांति की मुख्य शक्ति के रूप में किसान वर्ग।
(D) संसदीय चुनाव जीतने का महत्व।

78. चर्च और राज्य के बीच मध्यकालीन राजनीतिक चिंतन में प्राथमिक संघर्ष किस विषय पर था?
(A) बिशपों और चर्च के अधिकारियों को नियुक्त करने का अधिकार।
(B) आराधना की भाषा।
(C) सामंती भूमि के सिद्धांतों।
(D) कैथेड्रल वास्तुकला का डिजाइन।

79. "परिणाम की समानता" की अवधारणा का तात्पर्य है:
(A) सभी को एक ही बिंदु से शुरुआत करनी चाहिए।
(B) सभी के पास सफल होने का समान अवसर होना चाहिए।
(C) राज्य को संपत्ति की असमानताओं को कम करने के लिए कार्य करना चाहिए।
(D) कानून सभी पर समान रूप से लागू होना चाहिए।

80. निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें:
1. माओ की सांस्कृतिक क्रांति की शुरुआत।
2. रूस में लेनिन की बोल्शेविक क्रांति।
3. गांधी की दांडी यात्रा।
(A) 1, 3, 2
(B) 2, 3, 1
(C) 3, 2, 1
(D) 2, 1, 3

81. डेविड ईस्टन द्वारा सूचीबद्ध व्यवहारवाद के आठ "बौद्धिक आधारशिलाओं" में से निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है?
(A) नियमितता
(B) सत्यापन
(C) परिमाणीकरण
(D) प्रासंगिकता

82. विचारधारा की भूमिका को व्यक्तियों के लिए "नक्शा" प्रदान करने के रूप में सबसे अच्छी तरह वर्णित किया गया है। इस रूपक का क्या तात्पर्य है?
(A) विचारधाराएँ मुद्दों को समझने का एक सरल तरीका प्रदान करती हैं।
(B) विचारधाराएँ हमेशा तथ्यात्मक रूप से सही और सटीक होती हैं।
(C) विचारधाराएँ कठोर होती हैं और दिशा परिवर्तन को रोकती हैं।
(D) किसी दिए गए क्षेत्र के लिए केवल एक ही विचारधारा सही हो सकती है।

83. लेनिन के विपरीत, गांधी के परिवर्तन के सिद्धांत ने किस पर जोर दिया?
(A) एक हिंसक विद्रोह की आवश्यकता।
(B) एक छोटे, गुप्त अग्रगामी दल का नेतृत्व।
(C) व्यक्तियों का नैतिक उत्थान।
(D) राज्य तंत्र पर कब्जा।

84. "प्रक्रियात्मक" और "सारवान" लोकतंत्र के बीच का अंतर हमें यह समझने में मदद करता है कि:
(A) राजतंत्र और गणतंत्र के बीच क्या अंतर है।
(B) औपचारिक संस्थान व्यवहार में लोकतांत्रिक क्यों नहीं हो सकते हैं।
(C) प्रत्यक्ष लोकतंत्र से प्रतिनिधि लोकतंत्र में विकास कैसे हुआ।
(D) लोकतांत्रिक राज्यों द्वारा अपनाई जाने वाली आर्थिक नीतियां।

85. अवधारणा को उसके प्राथमिक प्रस्तावक या जुड़ाव के साथ सुमेलित करें।
सूची I: (अवधारणा)
P. "सिद्धांत का पतन"
Q. सत्याग्रह
R. "प्रासंगिकता का सिद्धांत"
S. अग्रगामी दल
सूची II: (प्रस्तावक)
1. गांधी
2. लेनिन
3. ईस्टन (उत्तर-व्यवहारवाद)
4. ईस्टन (व्यवहारवाद)
(A) P-4, Q-1, R-3, S-2
(B) P-1, Q-2, R-3, S-4
(C) P-4, Q-3, R-1, S-2
(D) P-2, Q-1, R-4, S-3

Click Here to Buy book on Amazon

86. कौन सा कथन दो तलवारों के सिद्धांत के मूल सिद्धांत को सबसे सटीक रूप से दर्शाता है?
(A) इसने आध्यात्मिक और लौकिक के बीच अधिकार के विभाजन को प्रतिपादित किया।
(B) इसने पोप द्वारा शासित एक धर्मतंत्रीय राज्य की वकालत की।
(C) इसने राज्य के अधीन चर्च की अधीनता का तर्क दिया।
(D) यह पैदल सेना और घुड़सवार सेना से संबंधित एक सैन्य सिद्धांत था।

87. राजनीतिक सिद्धांत के "पुनरुत्थान" के लिए एक प्रमुख तर्क यह था कि व्यवहारवाद के कार्यप्रणाली पर ध्यान केंद्रित करने के कारण क्या हुआ था?
(A) न्याय और स्वतंत्रता की बेहतर समझ।
(B) प्रमुख सामाजिक संघर्षों का सफल समाधान।
(C) राजनीतिक चिंतन के इतिहास पर अत्यधिक जोर।
(D) तुच्छ शोध जिसने महत्वपूर्ण प्रश्नों की उपेक्षा की।

88. एक प्रगतिशील कराधान प्रणाली, जहाँ उच्च आय पर उच्च दरों पर कर लगाया जाता है, किस सिद्धांत का अनुप्रयोग है?
(A) वितरणात्मक न्याय
(B) व्यक्तिगत न्याय
(C) प्रक्रियात्मक न्याय
(D) प्रतिशोधक न्याय

89. एक सरकार जो बिना वारंट के अपने नागरिकों के निजी संचार की जासूसी करती है, वह मुख्य रूप से किस अवधारणा का उल्लंघन कर रही है?
(A) सकारात्मक स्वतंत्रता
(B) नकारात्मक स्वतंत्रता
(C) सामाजिक न्याय
(D) परिणाम की समानता

90. निम्नलिखित अभिकथन (A) और कारण (R) पर विचार करें।
अभिकथन (A): उत्तर-व्यवहारवाद ने व्यवहारवाद के तरीकों को छोड़ने की कोशिश नहीं की बल्कि उन्हें पूरक और पुनर्गठित करने की कोशिश की।
कारण (R): उत्तर-व्यवहारवादियों ने अनुभवजन्य शोध की उपयोगिता को स्वीकार किया लेकिन इस बात पर जोर दिया कि इसे वास्तविक दुनिया की समस्याओं की चिंता द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए।
(A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(D) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

91. निम्नलिखित में से कौन सा 'व्यक्तिगत न्याय' का एक उदाहरण है?
(A) एक व्यक्ति को प्रतिनिधित्व के साथ निष्पक्ष सुनवाई प्राप्त होना।
(B) पर्यावरण के नुकसान के लिए एक कंपनी द्वारा मुआवजा देना।
(C) एक सरकार द्वारा धन कम करने की नीति लागू करना।
(D) एक समुदाय द्वारा नया सार्वजनिक पार्क बनाने के लिए संगठित होना।

92. लेनिन के साम्राज्यवाद के सिद्धांत ने तर्क दिया कि पूंजीवादी राज्यों ने मुख्य रूप से अन्य देशों को उपनिवेश बनाया:
(A) लोकतांत्रिक मूल्यों और संस्थानों के प्रसार के लिए।
(B) नए बाजार और निवेश के अवसर खोजने के लिए।
(C) धार्मिक या नागरिक मिशन को पूरा करने के लिए।
(D) सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए।

93. नियुक्ति को लेकर पोप और धर्मनिरपेक्ष शासकों के बीच मध्यकालीन संघर्ष मौलिक रूप से किसके लिए संघर्ष था?
(A) चर्च के अधिकारियों की नियुक्ति पर नियंत्रण।
(B) किसानों से कर वसूलने का अधिकार।
(C) राज्य की आधिकारिक भाषा।
(D) सामंती उत्तराधिकार का निर्धारण।

94. दिए गए दो कथनों पर विचार करें और सही उत्तर चुनें:
कथन I: अवसर की समानता का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जीवन में सभी का शुरुआती बिंदु एक समान हो।
कथन II: परिणाम की समानता का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रयास या प्रतिभा की परवाह किए बिना सभी एक ही बिंदु पर समाप्त करें।
(A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं।
(C) कथन I सत्य है, लेकिन कथन II असत्य है।
(D) कथन I असत्य है, लेकिन कथन II सत्य है।

95. गांधी के दर्शन में, 'अहिंसा' का तात्पर्य है:
(A) पूर्ण सत्य।
(B) मन, वचन और कर्म से हिंसा न करना।
(C) स्व-शासन या आत्म-नियंत्रण।
(D) आर्थिक आत्मनिर्भरता।

96. व्यवहारवाद के लिए केंद्रीय "तथ्य-मूल्य द्विभाजन" यह मानता है कि:
(A) तथ्यात्मक कथन मूल्यों से अधिक महत्वपूर्ण हैं।
(B) वस्तुनिष्ठ कथन मानकीय कथनों से प्राप्त किए जा सकते हैं।
(C) कोई यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकता कि 'क्या होना चाहिए' केवल 'क्या है' के आधार पर।
(D) सभी तथ्य स्वाभाविक रूप से मूल्यों से भरे होते हैं।

97. उदार लोकतंत्र की मुख्य विशेषता क्या है?
(A) व्यक्तिगत अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रता का संरक्षण।
(B) एक ही पार्टी में सभी शक्ति का केंद्रीकरण।
(C) सभी प्रमुख उद्योगों का राज्य स्वामित्व।
(D) संविधान का नियमित निलंबन।

NODIA

98. इनमें से कौन सा एक वैचारिक कथन का उदाहरण है?
(A) "समानता सुनिश्चित करने के लिए राज्य को उत्पादन का स्वामित्व रखना चाहिए।"
(B) "मुद्रास्फीति की वर्तमान दर 3% है।"
(C) "विधायिका ने पिछले सत्र में 57 विधेयक पारित किए।"
(D) "देश की राजधानी नई दिल्ली है।"

99. माओ की "नई जनवाद" की अवधारणा किसके लिए एक संक्रमणकालीन चरण थी?
(A) उन्नत पूंजीवादी देश।
(B) अर्ध-सामंती और अर्ध-औपनिवेशिक देश।
(C) सोवियत संघ।
(D) उत्तर-औद्योगिक समाज।

100. मध्यकालीन चर्च-राज्य संबंधों के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करें:
I. यह एक ही सिद्धांत द्वारा परिभाषित एक स्थिर संबंध था।
II. 'प्लेनिटूडो पोटेस्टेटिस' के पापल दावों ने धर्मनिरपेक्ष अधिकार को चुनौती दी।
III. पादुआ के मार्सिलियस ने धर्मनिरपेक्ष राज्य की सर्वोच्चता का तर्क दिया।
उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) केवल I और II
(B) केवल II और III
(C) केवल I और III
(D) I, II और III

101. "राजनीतिक सिद्धांत के पतन" का एक प्राथमिक कारण तार्किक प्रत्यक्षवाद का उदय था, जिसने तर्क दिया कि:
(A) ज्ञान तर्क और जन्मजात विचारों पर आधारित होना चाहिए।
(B) राजनीतिक अवधारणाओं को समझने के लिए संदर्भ ही कुंजी है।
(C) मानकीय कथन अर्थहीन हैं क्योंकि उनमें सत्यापन का अभाव है।
(D) संस्थागत अध्ययन विज्ञान का एकमात्र वैध रूप है।

102. स्वतंत्रता के संदर्भ में, 'क्षति का सिद्धांत' यह सुझाव देता है कि:
(A) राज्य केवल दूसरों को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए हस्तक्षेप कर सकता है।
(B) वे सभी कार्य जो स्वयं को नुकसान पहुँचाते हैं, प्रतिबंधित होने चाहिए।
(C) सुरक्षा की खातिर स्वतंत्रता का बलिदान दिया जाना चाहिए।
(D) राज्य को जबरदस्ती के माध्यम से सामुदायिक लाभ को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना चाहिए।

103. कौन सा विचारक इस विचार से सबसे अधिक जुड़ा है कि कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यों का मार्गदर्शन "जन-लाइन" को करना चाहिए?
(A) लेनिन
(B) गांधी
(C) माओ
(D) मार्क्स

104. "व्यक्तिगत न्याय" का मूल विचार किसके साथ सबसे निकटता से जुड़ा है?
(A) समुदाय की परंपराएं।
(B) शास्त्रीय उदारवाद के सिद्धांत।
(C) समाजवादी विचारधारा के लक्ष्य।
(D) सामूहिक जिम्मेदारी की अवधारणा।

105. उत्तर-व्यवहारवाद को सबसे अच्छी तरह इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है:
(A) शुद्ध औपचारिकतावाद की ओर वापसी।
(B) परंपरावाद और व्यवहारवाद का संश्लेषण।
(C) विज्ञान की अस्वीकृति।
(D) मूल्य-मुक्त शोध का समर्थन।

106. मध्यकालीन यूरोप में, 'सेसरडोटियम' शब्द किसके अधिकार क्षेत्र को संदर्भित करता है?
(A) पुरोहितीय या आध्यात्मिक अधिकार।
(B) शाही अधिकार।
(C) सामंती दायित्व।
(D) आर्थिक उत्पादन।

107. निम्नलिखित में से कौन सा "प्रक्रियात्मक लोकतंत्र" को सबसे अच्छी तरह परिभाषित करता है?
(A) शासन के संस्थानों और नियमों पर जोर देने वाली प्रणाली।
(B) ऐसी प्रणाली जहाँ परिणाम हमेशा निष्पक्ष और न्यायपूर्ण होते हैं।
(C) ऐसी प्रणाली जहाँ नागरिक सीधे सभी कानूनों पर मतदान करते हैं।
(D) ऐसी प्रणाली जहाँ एक बुद्धिमान अभिजात वर्ग दूसरों के लिए निर्णय लेता है।

108. निम्नलिखित में से कौन सा समानता का एक रूप नहीं है?
(A) कानूनी समानता
(B) राजनीतिक समानता
(C) सामाजिक समानता
(D) अभिजात वर्ग की समानता

109. गांधी की 'स्वदेशी' की अवधारणा मुख्य रूप से किससे संबंधित है?
(A) राजनीतिक स्वतंत्रता।
(B) धार्मिक सहिष्णुता।
(C) आर्थिक आत्मनिर्भरता।

Downloaded from www.pdf.tube

(D) सैन्य शक्ति।

110. शब्द को उसकी संबंधित विचारधारा के साथ सुमेलित करें।
सूची I: (शब्द)
P. तथ्य-मूल्य द्विभाजन
Q. प्लेनिटूडो पोटेस्टेटिस
R. सत्याग्रह
S. प्रासंगिकता का सिद्धांत
सूची II: (विचारधारा)
1. उत्तर-व्यवहारवाद
2. गांधीवादी
3. व्यवहारवाद
4. मध्यकालीन पापल सिद्धांत
(A) P-3, Q-4, R-2, S-1
(B) P-1, Q-2, R-3, S-4
(C) P-3, Q-1, R-4, S-2
(D) P-4, Q-3, R-2, S-1

111. "सामाजिक न्याय" की मांग मुख्य रूप से इस मान्यता से उत्पन्न हुई कि:
(A) कानूनी प्रणाली को धीमा और अक्षम माना गया था।
(B) राज्य बहुत शक्तिशाली हो रहा था और उसे नियंत्रण की आवश्यकता थी।
(C) व्यक्तिगत लेनदेन हमेशा निष्पक्ष और संतुलित थे।
(D) औपचारिक समानता गहरी सामाजिक असमानताओं को दूर करने में विफल रही।

112. लेनिन के अनुसार, रूस में बोल्शेविक क्रांति आवश्यक थी क्योंकि:
(A) रूस ने पहले ही पूर्ण पैमाने पर पूंजीवाद हासिल कर लिया था।
(B) बुर्जुआ वर्ग लोकतांत्रिक क्रांति के लिए बहुत कमजोर था।
(C) किसान सामंतवाद की ओर लौटने की मांग कर रहे थे।
(D) ज़ार शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण के लिए सहमत हो गए थे।

113. "राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान" में एक प्रमुख विषय किसकी आलोचना थी?
(A) न्याय
(B) स्वतंत्रता
(C) सापेक्षवाद
(D) लोकतंत्र

114. "दो तलवारों का सिद्धांत" एक रूपक था जिसका उपयोग किया गया था:
(A) धर्मयुद्ध जैसे धार्मिक युद्धों को सही ठहराने के लिए।
(B) राज्य की शाखाओं के बीच शक्ति के विभाजन की व्याख्या करने के लिए।
(C) आध्यात्मिक और लौकिक अधिकार के बीच के विभाजन का वर्णन करने के लिए।
(D) एक शांतिवादी राजनीतिक दर्शन का तर्क देने के लिए।

115. निम्नलिखित अभिकथन (A) और कारण (R) पर विचार करें।
अभिकथन (A): एक उदार लोकतंत्र में बहुमत की शक्ति निरपेक्ष नहीं होती है।
कारण (R): उदार लोकतंत्र सरकार पर संवैधानिक सीमाओं और अल्पसंख्यक अधिकारों के संरक्षण द्वारा चिह्नित होते हैं।
(A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(D) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

116. उत्तर-व्यवहारवाद के "कार्रवाई" पर जोर देने का अर्थ था कि राजनीतिक वैज्ञानिकों को:
(A) सक्रिय रूप से राजनीतिज्ञ बनने की कोशिश करनी चाहिए।
(B) कार्य के माध्यम से एक बेहतर समाज बनाने में संलग्न होना चाहिए।
(C) केवल अधिक डेटा एकत्र करने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए।
(D) सभी कार्रवाइयों से तटस्थ और अलग रहना चाहिए।

NODIA

117. एक विचारधारा जो मौजूदा सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था को संरक्षित करना चाहती है, उसे सबसे अच्छी तरह वर्णित किया जा सकता है:
(A) कट्टरपंथी
(B) क्रांतिकारी
(C) रूढ़िवादी
(D) अराजकतावादी

118. कौन सी अवधारणा व्यक्तिगत आचरण के बजाय समाज की बुनियादी संरचना में निष्पक्षता से मुख्य रूप से संबंधित है?
(A) व्यक्तिगत न्याय
(B) सामाजिक न्याय
(C) प्रतिशोधक न्याय
(D) विनिमय न्याय

119. माओवाद की एक परिभाषित विशेषता किसका सिद्धांत है?
(A) स्थायी क्रांति
(B) एक देश में समाजवाद
(C) लंबी अवधि का जनयुद्ध
(D) राज्य का विलोप

120. प्रभाव के आधार पर निम्नलिखित को कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करें:
1. लेनिन की "क्या किया जाना चाहिए?"
2. पोप जेलासियस I का "डुओ सुंट" पत्र।
3. डेविड ईस्टन की आलोचना जिसके कारण उत्तर-व्यवहारवाद का उदय हुआ।
(A) 1, 2, 3

(B) 2, 1, 3
(C) 3, 1, 2
(D) 2, 3, 1

121. दिए गए दो कथनों पर विचार करें और सही उत्तर चुनें:
कथन I: नकारात्मक स्वतंत्रता हस्तक्षेप 'से' मुक्ति है।
कथन II: सकारात्मक स्वतंत्रता आत्म-साक्षात्कार प्राप्त करने 'की' स्वतंत्रता है।
(A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं।
(C) कथन I सत्य है, लेकिन कथन II असत्य है।
(D) कथन I असत्य है, लेकिन कथन II सत्य है।

122. "दो तलवारों" के जेलासियन सिद्धांत का मूल उद्देश्य था:
(A) सम्राट पर पापल सर्वोच्चता का दावा करना।
(B) चर्च और राज्य के लिए अलग-अलग क्षेत्रों को परिभाषित करना।
(C) पोप पर शाही सर्वोच्चता का दावा करना।
(D) धर्मतंत्र के पक्ष में राजशाही को समाप्त करना।

123. निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहारवाद का सिद्धांत है?
(A) मानकीय सिद्धांत पर जोर
(B) मूल्य-आधारित शोध अपरिहार्य है
(C) तथ्य और मूल्य का पृथक्करण
(D) परिमाणीकरण की अस्वीकृति

124. गांधी के लिए, आदर्श राज्य है:
(A) एक शक्तिशाली, केंद्रीकृत राष्ट्र-राज्य।
(B) कमान अर्थव्यवस्था वाला एक समाजवादी राज्य।
(C) विकेंद्रीकृत गांवों पर आधारित एक राज्यविहीन समाज।
(D) सीमित शक्तियों वाला एक संवैधानिक राजतंत्र।

125. लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
I. लोकतंत्र के लिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की आवश्यकता होती है।
II. बड़े राज्यों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र अधिक व्यावहारिक है।
III. राजनीतिक समानता लोकतांत्रिक सिद्धांत का केंद्र है।
उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) केवल III
(B) केवल I और II
(C) केवल II और III
(D) I, II और III

126. "राजनीतिक सिद्धांत का पुनरुत्थान" को 1971 की किस ऐतिहासिक पुस्तक के प्रकाशन से दर्शाया जाता है?
(A) डेविड ईस्टन द्वारा "द पॉलिटिकल सिस्टम"
(B) जॉन रॉल्स द्वारा "ए थ्योरी ऑफ जस्टिस"
(C) कार्ल मार्क्स द्वारा "दास कैपिटल"
(D) निकोलो मैकियावेली द्वारा "द प्रिंस"

127. लेनिन की "अग्रगामी दल" की थ्योरी उनके किस विश्वास की प्रतिक्रिया थी:
(A) श्रमिक वर्ग स्वतः ही चेतना विकसित कर लेगा।
(B) बुर्जुआ वर्ग को सत्ता छोड़ने के लिए राजी किया जा सकता है।
(C) श्रमिक स्वतःस्फूर्तता केवल ट्रेड यूनियनवाद की ओर ले जाएगी।
(D) किसान वर्ग सबसे क्रांतिकारी वर्ग था।

128. सामाजिक न्याय का समर्थक निम्नलिखित में से किस नीति का सबसे अधिक समर्थन करेगा?
(A) सभी करों को समाप्त करना।
(B) सार्वजनिक शिक्षा के लिए प्रगतिशील कराधान लागू करना।
(C) सभी सरकारी स्कूलों का निजीकरण करना।
(D) व्यवसायों पर से सभी नियमों को हटाना।

129. लेनिन और माओ के क्रांति के सिद्धांतों के बीच मुख्य अंतर किसमें निहित है:
(A) माओ द्वारा हिंसा की अस्वीकृति।
(B) शहरी सर्वहारा बनाम ग्रामीण किसान वर्ग की भूमिका।
(C) वर्गविहीन समाज प्राप्त करने का लक्ष्य।
(D) एक अनुशासित पार्टी का महत्व।

130. मध्यकालीन विचार कि राज्य का उद्देश्य व्यवस्था बनाए रखना है, जिससे चर्च आत्माओं का मार्गदर्शन कर सके, क्या दर्शाता है?
(A) शक्तियों के पृथक्करण का प्रारंभिक सिद्धांत।
(B) चर्च-राज्य संबंधों का एक सहकारी दृष्टिकोण।
(C) चर्च पर राज्य का पूर्ण प्रभुत्व।
(D) अराजकतावादी सिद्धांत।

131. निम्नलिखित में से कौन सी विचारधारा की विशेषता नहीं है?
(A) यह मौजूदा व्यवस्था की व्याख्या प्रदान करती है।
(B) यह एक वांछित भविष्य का मॉडल प्रदान करती है।
(C) यह परिवर्तन के लिए कार्रवाई के कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करती है।
(D) यह एक विशुद्ध वस्तुनिष्ठ और वैज्ञानिक विवरण है।

132. "राजनीतिक सिद्धांत के पतन" के शोध प्रबंध ने तर्क दिया कि सिद्धांत किसके द्वारा नष्ट हो गया था?
(A) राजतंत्रों के उदय से।
(B) शास्त्रीय भाषाओं पर अत्यधिक जोर देने से।
(C) इतिहासवाद और प्रत्यक्षवाद की शक्तियों से।
(D) सार्वजनिक जीवन में धर्म के पतन से।

133. "अवसर की समानता" की अवधारणा को उन आलोचकों द्वारा चुनौती दी जाती है जो तर्क देते हैं कि:
(A) योग्यता के आधार पर लोगों को पुरस्कृत करना अनुचित है।
(B) इसके लिए स्थिति की अंतर्निहित असमानताओं को दूर

Click Here to Buy book on Amazon

करने की आवश्यकता है।
(C) यह सीधे अधिनायकवाद की ओर ले जाता है।
(D) यह व्यक्तिगत अधिकारों पर बहुत अधिक जोर देता है।

134. उत्तर-व्यवहारवादी आंदोलन की केंद्रीय मांग निम्नलिखित में से कौन सी थी?
(A) अपने आप में परिमाणीकरण पर अधिक ध्यान देना।
(B) सामाजिक समस्याओं के लिए शोध की अधिक प्रासंगिकता।
(C) एकमात्र फोकस के रूप में संवैधानिक कानून पर वापसी।
(D) राजनीति विज्ञान को अन्य विज्ञानों से अलग करना।

135. राजनीतिक विचार को उस विचारक के साथ सुमेलित करें जो इसके साथ सबसे निकटता से जुड़ा है।
सूची I: (विचार)
P. नकारात्मक बनाम सकारात्मक स्वतंत्रता
Q. न्याय का सिद्धांत
R. शक्ति-ज्ञान
S. अग्रगामी दल
सूची II: (विचारक)
1. जॉन रॉल्स
2. मिशेल फौकॉल्ट
3. लेनिन
4. यशायाह बर्लिन
(A) P-4, Q-1, R-2, S-3
(B) P-1, Q-4, R-3, S-2
(C) P-4, Q-2, R-1, S-3
(D) P-3, Q-1, R-2, S-4

136. निष्पक्ष सुनवाई का व्यक्ति का अधिकार, जिसमें निर्दोषता का अनुमान शामिल है, किस श्रेणी में आता है?
(A) सामाजिक न्याय
(B) वितरणात्मक न्याय
(C) प्रक्रियात्मक न्याय
(D) आर्थिक न्याय

137. गांधी की 'ग्राम स्वराज' की अवधारणा किसके प्रति उनकी प्रतिबद्धता का एक उदाहरण है?
(A) केंद्रीकृत योजना
(B) औद्योगिकीकरण
(C) राजनीतिक और आर्थिक विकेंद्रीकरण
(D) एक मजबूत सेना

138. यह तर्क कि राजनीतिक सिद्धांत "मृत" हो गया था, किसके द्वारा चिह्नित "पुनरुत्थान" द्वारा प्रतिवादित किया गया था?
(A) व्यवहारवाद की पूर्ण विजय।
(B) मानकीय प्रश्नों में नए सिरे से रुचि।
(C) केवल क्षेत्र अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करना।
(D) सभी अनुभवजन्य विधियों की अस्वीकृति।

139. माओवादी सिद्धांत में "संयुक्त मोर्चा" की क्या भूमिका है?
(A) शत्रुओं के विरुद्ध देशभक्त वर्गों के साथ सर्वहारा वर्ग को एकजुट करना।
(B) साम्राज्यवादी शक्तियों के साथ गठबंधन बनाना।
(C) कम्युनिस्ट पार्टी का अन्य राजनीतिक दलों के साथ विलय करना।
(D) एक एकल वैश्विक सरकार बनाना।

140. निम्नलिखित अभिकथन (A) और कारण (R) पर विचार करें।
अभिकथन (A): राजनीति विज्ञान में व्यवहारवादी दृष्टिकोण मूल्य-तटस्थता पर जोर देता है।
कारण (R): यह मानता है कि वैज्ञानिक जांच उन तथ्यों के कथनों तक सीमित होनी चाहिए जिनका अनुभवजन्य परीक्षण किया जा सके।
(A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(D) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

141. वह सिद्धांत कि पोप दोनों मामलों में अंतिम अधिकार रखता है और शासकों को लौकिक अधिकार सौंपता है, वह है:
(A) पापल सर्वोच्चता का सिद्धांत
(B) जेलासियन सिद्धांत
(C) कौंसिलियर आंदोलन
(D) राजाओं का दैवीय अधिकार

142. स्वतंत्रता और उच्छृंखलता के बीच अंतर यह है कि:
(A) स्वतंत्रता निरपेक्ष है, जबकि उच्छृंखलता सीमित है।
(B) स्वतंत्रता मुक्ति है, जबकि उच्छृंखलता जिम्मेदारी है।
(C) स्वतंत्रता में जिम्मेदारी निहित है; उच्छृंखलता अनियंत्रित होती है।
(D) कोई अंतर नहीं है; ये शब्द पर्यायवाची हैं।

NODIA

143. कार्यरूप में सारवान लोकतंत्र का सबसे अच्छा उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है?
(A) हर चार साल में चुनाव कराना।
(B) एक कानून जो प्रभावी रूप से बाल गरीबी को कम करता है।
(C) एक लिखित संविधान का होना।
(D) कई राजनीतिक दलों का अस्तित्व।

144. लेनिन के अनुसार, राज्य क्या है?
(A) प्रतिस्पर्धी सामाजिक वर्गों के बीच एक तटस्थ मध्यस्थ।
(B) एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के उत्पीड़न का साधन।
(C) अधिकारों की रक्षा के लिए एक सामाजिक अनुबंध का उत्पाद।
(D) ईश्वर द्वारा निर्धारित एक दैवीय संस्था।

145. "कानून की उचित प्रक्रिया" किसका एक मौलिक सिद्धांत है?
(A) सामाजिक न्याय
(B) व्यक्तिगत न्याय

(C) धर्मतंत्रीय न्याय
(D) आर्थिक न्याय

146. दिए गए दो कथनों पर विचार करें और सही उत्तर चुनें:
कथन I: "राजनीतिक सिद्धांत का पतन" महान, मानकीय सिद्धांत-निर्माण से दूर जाने को संदर्भित करता है।
कथन II: "राजनीतिक सिद्धांत का पुनरुत्थान" न्याय और अधिकारों के बारे में प्रश्नों की वापसी द्वारा चिह्नित किया गया था।
(A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं।
(C) कथन I सत्य है, लेकिन कथन II असत्य है।
(D) कथन I असत्य है, लेकिन कथन II सत्य है।

147. गांधीवादी और माओवादी परिवर्तन के सिद्धांतों के बीच एक मुख्य अंतर निम्नलिखित में से किस पर उनका रुख है?
(A) जनता की भूमिका
(B) नेतृत्व का महत्व
(C) हिंसा का उपयोग
(D) सामाजिक समानता का लक्ष्य

148. "क्रिश्चियनडम" की मध्यकालीन अवधारणा का तात्पर्य था:
(A) धार्मिक स्वतंत्रता वाला एक धर्मनिरपेक्ष समाज।
(B) ऐसा समाज जहाँ धार्मिक और राजनीतिक जीवन आपस में जुड़े हुए थे।
(C) चर्च और राज्य का पूर्ण पृथक्करण।
(D) प्रत्यक्ष लोकतंत्र पर आधारित एक राजनीतिक प्रणाली।

149. एक विचारधारा राजनीतिक व्यवस्था को वैध बनाने का कार्य करती है। इसका अर्थ है कि यह:
(A) प्रणाली के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करती है।
(B) शक्ति संरचनाओं के लिए नैतिक वैधता की भावना उत्पन्न करती है।
(C) यह सुनिश्चित करती है कि प्रणाली आर्थिक रूप से कुशल है।
(D) गारंटी देती है कि प्रणाली लोकतांत्रिक है।

150. परिवर्तन के सिद्धांतों के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करें:
I. लेनिन ने सर्वहारा वर्ग के नेतृत्व में दो चरणों वाली क्रांति की वकालत की।
II. माओ ने किसान वर्ग पर ध्यान केंद्रित करते हुए मार्क्सवाद को कृषि संदर्भ में ढाला।
III. गांधी ने अहिंसक सामाजिक पुनर्निर्माण का प्रस्ताव दिया।
उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) केवल I और II
(B) केवल II और III
(C) केवल I और III
(D) I, II और III

151. सकारात्मक स्वतंत्रता के विरुद्ध अक्सर दी जाने वाली आलोचना निम्नलिखित में से कौन सी है?
(A) यह बहुत अधिक व्यक्तिवादी है और समुदाय की उपेक्षा करती है।
(B) इसका उपयोग राज्य के संरक्षकवाद को सही ठहराने के लिए किया जा सकता है।
(C) यह किसी भी राज्य के हस्तक्षेप की अनुमति नहीं देती है।
(D) यह अराजकता का पर्याय है।

152. उत्तर-व्यवहारवादी क्रांति किसका आह्वान थी?
(A) अनुभवजन्य शोध को त्यागने का।
(B) राजनीति विज्ञान को अधिक प्रासंगिक बनाने का।
(C) विशेष रूप से पश्चिमी राजनीतिक चिंतन पर ध्यान केंद्रित करने का।
(D) राजनीति विज्ञान को नीतिशास्त्र से अलग करने का।

153. मध्यकाल में, पदनियुक्ति विवाद किसका स्पष्ट उदाहरण था?
(A) आध्यात्मिक और लौकिक शक्तियों के बीच संघर्ष।
(B) ट्रिनिटी की प्रकृति के बारे में एक धार्मिक बहस।
(C) सामंती दायित्वों के विरुद्ध एक किसान विद्रोह।
(D) नगर-राज्यों के बीच व्यापार मार्गों को लेकर विवाद।

154. सामाजिक न्याय का प्राथमिक ध्यान क्या है?
(A) गलत करने वालों को दंडित करना।
(B) समाज की बुनियादी संरचना की निष्पक्षता।
(C) यह सुनिश्चित करना कि व्यक्तियों के बीच अनुबंधों का सम्मान किया जाए।
(D) कानूनी प्रणाली की प्रक्रियाएं।

155. "सौ फूलों को खिलने दो" का नारा किसके द्वारा शुरू किए गए उदारीकरण के दौर से जुड़ा था?
(A) लेनिन
(B) गांधी
(C) माओ
(D) डेविड ईस्टन

156. एक प्रतिनिधि लोकतंत्र में, जवाबदेही के सिद्धांत का अर्थ है कि:
(A) प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह नहीं हैं।
(B) लोगों को यह जानने का अधिकार है कि उनकी सरकार कैसे चलाई जा रही है।
(C) निर्वाचित अधिकारियों को अपने कार्यों के लिए नागरिकों को जवाब देना होगा।
(D) केवल सरकारी लेखाकार ही सार्वजनिक धन के लिए जिम्मेदार हैं।

157. निम्नलिखित में से कौन सी व्यवहारवाद की मुख्य विशेषता नहीं है?
(A) राजनीति विज्ञान का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ एकीकरण।
(B) मूल्य-तटस्थ दृष्टिकोण पर जोर।

NODIA

(C) मानकीय और दार्शनिक प्रश्नों पर जोर।
(D) राजनीतिक व्यवहार में नियमितताओं की खोज।

158. समानता की कौन सी अवधारणा व्यक्तिगत आवश्यकताओं की परवाह किए बिना, सभी परिस्थितियों में समान व्यवहार का तर्क देती है?
(A) आधारभूत समानता
(B) अवसर की समानता
(C) परिणाम की समानता
(D) आनुपातिक समानता

159. लेनिन के लिए, साम्राज्यवाद राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण था क्योंकि इसने:
(A) समाजवादी क्रांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्थितियाँ पैदा कीं।
(B) पूंजीवाद की सफलता को दिखाया।
(C) राष्ट्रों के बीच शांति को बढ़ावा दिया।
(D) राज्य के पतन का मार्ग प्रशस्त किया।

160. ऐतिहासिक प्रमुखता के आधार पर निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें:
1. "प्रासंगिकता का सिद्धांत"
2. दो तलवारों का सिद्धांत
3. "तथ्य-मूल्य द्विभाजन"
(A) 1, 3, 2
(B) 2, 3, 1
(C) 3, 1, 2
(D) 2, 1, 3

161. एक विचारधारा जो समाज की आलोचना करती है और एक मौलिक रूप से भिन्न भविष्य का प्रस्ताव देती है, उसे क्या कहा जाता है?
(A) रुढ़िवादी विचारधारा
(B) क्रांतिकारी विचारधारा
(C) प्रतिक्रियावादी विचारधारा
(D) सुधारवादी विचारधारा

162. राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान को अक्सर व्यवहारवाद की किस कमी के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में देखा जाता है?
(A) मतदान मशीनों के तकनीकी पहलू।
(B) सामाजिक न्याय के मुद्दे और राजनीतिक जीवन का उद्देश्य।
(C) विधायी शाखा का बजट।
(D) राजनयिक संबंधों का इतिहास।

163. गांधीवादी सत्याग्रह का मूल सिद्धांत क्या है?
(A) विरोधी को कष्ट पहुँचाना।
(B) अंतरात्मा को अपील करने के लिए स्वयं कष्ट सहना।
(C) रणनीतिक, सीमित हिंसा का उपयोग करना।
(D) राजनीतिक जुड़ाव से पूरी तरह पीछे हट जाना।

164. दिए गए दो कथनों पर विचार करें और सही उत्तर चुनें:
कथन I: व्यक्तिगत न्याय मुख्य रूप से निष्पक्ष प्रक्रियाओं और व्यक्तियों के अधिकारों पर केंद्रित है।
कथन II: सामाजिक न्याय पूरे समाज में वस्तुओं और संसाधनों के वितरण से संबंधित है।
(A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं।
(C) कथन I सत्य है, लेकिन कथन II असत्य है।
(D) कथन I असत्य है, लेकिन कथन II सत्य है।

165. अवधारणा को उसके सही विवरण के साथ सुमेलित करें।
सूची I: (अवधारणा)
P. सारवान लोकतंत्र
Q. प्रक्रियात्मक लोकतंत्र
R. नकारात्मक स्वतंत्रता
S. सामाजिक न्याय
सूची II: (विवरण)
1. औपचारिक नियमों पर केंद्रित
2. जीवन की गुणवत्ता पर केंद्रित
3. असमानता को सुधारता है
4. मजबूरी से मुक्ति
(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-2, Q-1, R-4, S-3
(C) P-3, Q-4, R-1, S-2
(D) P-2, Q-3, R-4, S-1

166. मध्यकालीन चिंतन के संदर्भ में, राज्य को अक्सर चर्च के लिए 'ब्रैकियम सेकुलारे' के रूप में देखा जाता था, जिसका अर्थ था कि उससे अपेक्षा की जाती थी:
(A) चर्च के प्रभाव से स्वतंत्र होकर शासन करना।
(B) चर्च की इच्छा को लागू करने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करना।
(C) चर्च के साथ निरंतर संघर्ष की स्थिति में रहना।
(D) विशेष रूप से आर्थिक मामलों पर ध्यान केंद्रित करना।

167. "तकनीक" व्यवहारवाद की एक "बौद्धिक आधारशिला" थी। यह किसे संदर्भित करता है?
(A) प्राचीन दार्शनिक तकनीकों पर ध्यान।
(B) सटीक डेटा का विश्लेषण करने के लिए शोध विधियों का उपयोग।
(C) लॉबिस्टों द्वारा उपयोग की जाने वाली राजनीतिक तकनीकें।
(D) सभी तकनीकी शब्दावली से बचना।

168. माओ के परिवर्तन के सिद्धांत में, "सांस्कृतिक क्रांति" किसके विरुद्ध संघर्ष के रूप में अभीष्ट थी?
(A) विदेशी साम्राज्यवादी शक्तियों के।
(B) सामंती जमींदारी के अवशेषों के।
(C) स्वयं कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर संशोधनवाद के।
(D) सोवियत साम्यवाद के प्रभाव के।

Downloaded from www.pdf.tube

169. कानूनी समानता, या "कानून के समक्ष समानता" का अर्थ है कि:
(A) सभी व्यक्तियों के पास धन का समान स्तर है।
(B) कानून सभी नागरिकों पर निष्पक्ष रूप से लागू होता है।
(C) सभी कानूनों को प्रत्यक्ष वोट द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए।
(D) हर कोई समान परिणामों का हकदार है।

170. निम्नलिखित अभिकथन (A) और कारण (R) पर विचार करें।
अभिकथन (A): गांधी का परिवर्तन का सिद्धांत आध्यात्मिकता और नैतिकता में गहराई से निहित है।
कारण (R): सत्य और अहिंसा जैसी अवधारणाएं नैतिक अनिवार्यताएं हैं जो सभी कार्यों का मार्गदर्शन करती हैं।
(A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(D) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

171. "राजनीतिक सिद्धांत के पतन" शोध प्रबंध मुख्य रूप से किस क्षेत्र में अनुशासन की स्थिति पर एक टिप्पणी थी?
(A) लैटिन अमेरिका
(B) एशिया
(C) एंग्लो-अमेरिकन दुनिया
(D) पूर्वी यूरोप

172. राजनीतिक मूल्यों के रूप में स्वतंत्रता और समानता के बीच एक मुख्य अंतर क्या है?
(A) समानता को बढ़ावा देने के लिए कुछ स्वतंत्रताओं को सीमित करने की आवश्यकता हो सकती है।
(B) स्वतंत्रता एक सामूहिक अवधारणा है जबकि समानता व्यक्तिवादी है।
(C) सभी राजनीतिक विचारक सहमत हैं कि वे पूरी तरह से अनुकूल हैं।
(D) स्वतंत्रता एक आधुनिक मूल्य है, जबकि समानता एक प्राचीन मूल्य है।

173. निम्नलिखित में से कौन सी एक सर्वाधिकारवादी विचारधारा की विशेषता नहीं है?
(A) यह सत्य का सर्वांगीण दृष्टिकोण प्रदान करती है।
(B) इसका उद्देश्य पूरे समाज को बदलना है।
(C) यह विचारों की विविधता को प्रोत्साहित करती है।
(D) यह दूर करने के लिए एक विशिष्ट शत्रु समूह की पहचान करती है।

174. न्याय की अवधारणा जो "प्रत्येक व्यक्ति को उसका हक देने" पर ध्यान केंद्रित करती है, एक शास्त्रीय परिभाषा है जिसका श्रेय दिया जाता है:
(A) प्राचीन ग्रीक और रोमन दार्शनिकों को।
(B) आधुनिक व्यवहारवादियों को।
(C) मध्यकालीन धर्मशास्त्रियों को।
(D) उत्तर-आधुनिक विचारकों को।

175. लेनिन और माओ दोनों के लिए क्रांति का अंतिम लक्ष्य क्या था?
(A) एक उदार लोकतंत्र की स्थापना।
(B) एक वर्गविहीन, कम्युनिस्ट समाज का निर्माण।
(C) एक पारंपरिक राजतंत्र की बहाली।
(D) वैश्विक मुक्त बाजार का कार्यान्वयन।

176. निम्नलिखित में से कौन व्यवहारवाद को उत्तर-व्यवहारवाद से सही ढंग से अलग करता है?
(A) व्यवहारवाद मूल्यों पर जोर देता है।
(B) उत्तर-व्यवहारवाद अनुभवजन्य पद्धतियों के साथ प्रासंगिकता को एकीकृत करता है।
(C) व्यवहारवाद विशेष रूप से एक यूरोपीय आंदोलन था।
(D) उत्तर-व्यवहारवाद ने सभी मात्रात्मक डेटा को खारिज कर दिया।

NODIA

177. मध्यकालीन पोप द्वारा राजा को पदच्युत करने का दावा किसकी चरम अभिव्यक्ति थी?
(A) राजाओं का दैवीय अधिकार।
(B) लौकिक शक्ति पर आध्यात्मिक शक्ति की सर्वोच्चता।
(C) चर्च और राज्य की पूर्ण समानता।
(D) लोकप्रिय संप्रभुता का सिद्धांत।

178. एक सरकार जो अपने सभी नागरिकों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा की गारंटी देती है, वह किसे प्राथमिकता दे रही है?
(A) सकारात्मक स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय।
(B) नकारात्मक स्वतंत्रता।
(C) केवल प्रक्रियात्मक न्याय।
(D) अराजकता-पूंजीवाद।

179. गांधीवादी सिद्धांत 'स्वराज' का अर्थ यह भी है:
(A) दूसरे राष्ट्रों की विजय।
(B) स्व-शासन और अपनी इंद्रियों पर शासन।
(C) एक शक्तिशाली औद्योगिक अर्थव्यवस्था की स्थापना।
(D) बहुमत की पूर्ण शक्ति।

180. विचारधारा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
I. विचारधारा एक समुदाय के लिए सामाजिक जुड़ाव के रूप में कार्य कर सकती है।
II. विचारधारा हमेशा अतार्किक होती है।
III. राजनीतिक दल अक्सर विचारधाराओं के इर्द-गिर्द संगठित होते हैं।
उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) केवल I और III
(B) केवल II
(C) केवल I और II
(D) I, II और III

181. माओ का अंतर्विरोधों का सिद्धांत किसके लिए एक प्रमुख वैचारिक उपकरण था?
(A) नीतिगत बदलावों और राजनीतिक शुद्धिकरण को सही ठहराने के लिए।
(B) पश्चिम के साथ व्यापार समझौतों पर बातचीत करने के लिए।
(C) कलात्मक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए।
(D) प्रत्यक्ष लोकतंत्र को लागू करने के लिए।

182. लोकतांत्रिक सिद्धांत की एक मूल धारणा यह है कि:
(A) औसत नागरिक निर्णय लेने में असमर्थ है।
(B) राजनीतिक अधिकार सहमति से प्राप्त होना चाहिए।
(C) वंशानुगत शासन सबसे स्थिर रूप है।
(D) स्थिरता के लिए आर्थिक असमानता आवश्यक है।

183. "शुद्ध विज्ञान" व्यवहारवाद का एक लक्ष्य था। इसका क्या तात्पर्य था?
(A) राजनीति का अध्ययन तत्काल व्यावहारिक चिंता के बिना किया जाना चाहिए।
(B) केवल शुद्ध उद्देश्यों वाले वैज्ञानिकों को ही राजनीति का अध्ययन करना चाहिए।
(C) राजनीति विज्ञान का रसायन विज्ञान में विलय कर दिया जाना चाहिए।
(D) राजनीति के अध्ययन में नैतिक निर्णय शामिल होने चाहिए।

184. दो तलवारों के जेलासियन सिद्धांत को किसके प्रारंभिक प्रयास के रूप में देखा जा सकता है?
(A) सर्वाधिकारवादी नियंत्रण।
(B) शक्ति के अलग-अलग अधिकार क्षेत्रों को परिभाषित करने।
(C) नास्तिकता को राज्य नीति के रूप में स्थापित करने।
(D) नियंत्रण और संतुलन की प्रणाली बनाने।

185. यह अवधारणा कि न्याय के लिए हमें समान मामलों में समान व्यवहार करने की आवश्यकता है, क्या कहलाती है?
(A) औपचारिक न्याय का सिद्धांत।
(B) सामाजिक न्याय का सिद्धांत।
(C) दैवीय न्याय का सिद्धांत।
(D) क्रांतिकारी न्याय का सिद्धांत।

186. निम्नलिखित में से कौन सी गांधी के नए समाज के दृष्टिकोण की विशेषता नहीं है?
(A) ग्राम गणराज्यों पर आधारित एक विकेंद्रीकृत राजनीति।
(B) एक भारी औद्योगिक, शहरीकृत अर्थव्यवस्था।
(C) सत्य और अहिंसा पर आधारित एक सामाजिक व्यवस्था।
(D) आत्मनिर्भरता और शारीरिक श्रम पर जोर।

187. "राजनीतिक सिद्धांत के पतन और पुनरुत्थान" पर बहस मौलिक रूप से किसके बारे में थी?
(A) चुनावी प्रणाली का सबसे अच्छा रूप।
(B) अध्ययन की उचित पद्धति और उद्देश्य।
(C) संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति।
(D) रोमन साम्राज्य का इतिहास।

188. निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता और समानता के बीच तनाव को दर्शाता है?
(A) धन की असमानता को कम करने के लिए विरासत पर उच्च कर।
(B) सभी के लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देने वाला कानून।
(C) सभी अभियुक्तों के लिए निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार।
(D) सार्वभौमिक मताधिकार की स्थापना।

189. "साम्राज्यवाद" में लेनिन का प्रमुख सैद्धांतिक योगदान क्या था?
(A) यह तर्क देना कि पूंजीवाद स्वयं में सुधार कर सकता है।
(B) शांतिपूर्ण संक्रमण की वकालत करना।
(C) पश्चिमी क्रांति में देरी की व्याख्या करना।
(D) औपनिवेशिक शक्तियों के नागरिक मिशन की प्रशंसा करना।

190. प्रक्रियात्मक लोकतंत्र की एक प्रमुख आलोचना क्या है?
(A) यह महत्वपूर्ण सामाजिक अन्याय के साथ मौजूद रह सकता है।
(B) इसे लागू करना बहुत कठिन है।
(C) यह स्वाभाविक रूप से अस्थिर है।
(D) यह न्यायपालिका को बहुत अधिक शक्ति देता है।

191. लियो स्ट्रॉस और उनके अनुयायियों ने किसकी वकालत की?
(A) राजनीति को समझने के लिए सांख्यिकीय विधियों के उपयोग की।
(B) एक एकल एकीकृत सिद्धांत के विकास की।
(C) संस्थानों की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करने की।
(D) शास्त्रीय दर्शन के अध्ययन की ओर लौटने की।

192. "सामाजिक न्याय" की अवधारणा के लिए आवश्यक है कि हम इस पर ध्यान दें:
(A) केवल व्यक्तियों के कार्यों पर।
(B) संस्थानों द्वारा उत्पन्न लाभ के प्रतिमानों पर।
(C) औपचारिक शिष्टाचार के नियमों पर।
(D) राष्ट्रों के बीच ऐतिहासिक शिकायतों पर।

193. मध्यकालीन चर्च एक प्रमुख लौकिक शक्ति भी था क्योंकि यह:
(A) एक बड़ा भूस्वामी था।
(B) सेनाओं की कमान संभालता था और कर वसूलता था।
(C) अदालतों की एक विशाल प्रणाली चलाता था।
(D) उपरोक्त सभी।

194. चीन के अनुकूल माओ की विचारधारा का एक परिभाषित तत्व क्या था?

Click Here to Buy book on Amazon

(A) शहरी श्रमिक वर्ग पर इसका जोर।
(B) बहुदलीय चुनावों की इसकी वकालत।
(C) कन्फ्यूशियस मूल्यों का इसका प्रचार।
(D) किसान वर्ग की क्रांतिकारी क्षमता पर इसका ध्यान।

195. राजनीतिक विचारक को क्रांतिकारी परिवर्तन के बारे में उनके मूल विचार के साथ सुमेलित करें।
सूची I: (विचारक)
P. लेनिन
Q. माओ
R. गांधी
S. एडमंड बर्क
सूची II: (विचार)
1. सत्याग्रह
2. सतर्क सुधार
3. किसान-नेतृत्व वाला युद्ध
4. अग्रगामी दल
(A) P-4, Q-3, R-1, S-2
(B) P-3, Q-4, R-2, S-1
(C) P-4, Q-1, R-2, S-3
(D) P-1, Q-3, R-4, S-2

196. "जहाँ कोई कानून नहीं है, वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं है।" यह कथन सुझाव देता है कि:
(A) कानून और स्वतंत्रता परस्पर अनन्य हैं।
(B) अराजकता से स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कानून आवश्यक है।
(C) स्वतंत्रता बिना नियमों के प्राकृतिक अवस्था में मौजूद रह सकती है।
(D) जितने अधिक कानून, उतनी अधिक स्वतंत्रता।

197. उत्तर-व्यवहारवाद को सबसे अच्छी तरह किसके रूप में वर्णित किया गया है?
(A) वैज्ञानिक जांच को त्यागने का आह्वान।
(B) वैज्ञानिक जांच को अधिक प्रासंगिक बनाने का आह्वान।
(C) परंपरावादी दृष्टिकोण की ओर वापसी।
(D) मार्क्सवाद का एक नया रूप।

198. प्रगतिशील आयकर का औचित्य किसके सिद्धांतों के अनुरूप है?
(A) व्यक्तिगत न्याय
(B) प्रक्रियात्मक न्याय
(C) सामाजिक न्याय
(D) प्रतिशोधक न्याय

199. लोकतंत्र का केंद्रीय विचार क्या है?
(A) धनवानों का शासन।
(B) सर्वाधिक शिक्षितों का शासन।
(C) जनता का शासन।
(D) एक एकल नेता का शासन।

200. निम्नलिखित अभिकथन (A) और कारण (R) पर विचार करें।
अभिकथन (A): "दो तलवारों का सिद्धांत" मध्यकाल में निरंतर घर्षण का स्रोत था।
कारण (R): पापल और शाही दोनों पक्षों ने सर्वोच्चता का दावा करने के लिए सिद्धांत की व्याख्या की।
(A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(D) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

201. निम्नलिखित में से कौन सा गांधी के राज्य के दृष्टिकोण का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है?
(A) राज्य एक आवश्यक बुराई है जिसे शक्तिशाली होना चाहिए।
(B) राज्य हिंसा का प्रतिनिधित्व करने वाली एक "आत्मारहित मशीन" है।
(C) राज्य एक दैवीय संस्था है जिसकी आज्ञा मानी जानी चाहिए।
(D) राज्य न्याय के लिए एकमात्र विश्वसनीय उपकरण है।

202. व्यवहारवादी 'परिमाणीकरण' पर जोर देने का अर्थ था कि:
(A) शोध निष्कर्षों को जहाँ तक संभव हो संख्यात्मक रूप से व्यक्त किया जाना चाहिए।
(B) राजनीतिक विश्लेषण में केवल गुण मायने रखते हैं।
(C) ऐतिहासिक वृत्तांत डेटा का सबसे महत्वपूर्ण रूप थे।
(D) गणितीय सूत्रों से बचना चाहिए।

NODIA

203. कानूनी समानता और अवसर की समानता के बीच मुख्य अंतर क्या है?
(A) कानूनी समानता अनुप्रयोग है; अवसर शुरुआती बिंदु है।
(B) कानूनी समानता अपराधियों पर लागू होती है; अवसर सभी के लिए है।
(C) कोई अंतर नहीं है।
(D) कानूनी समानता समाजवादी है; अवसर पूंजीवादी है।

204. "शक्ति बंदूक की नली से निकलती है" यह कथन किसके विचारों का सारांश है?
(A) महात्मा गांधी
(B) जॉन लॉक
(C) यशायाह बर्लिन
(D) माओ जेदोंग

205. 'राजनीतिक सिद्धांत का पुनरुत्थान' किसकी नई सराहना का प्रतीक है?
(A) इस विचार की कि प्रश्नों का एक नैतिक आयाम होता है।
(B) इस विश्वास की कि सभी प्रश्नों को सांख्यिकी द्वारा हल किया जा सकता है।
(C) केवल संस्थागत नियमों पर ध्यान केंद्रित करने के महत्व की।
(D) इस सिद्धांत की कि राजनीति विशुद्ध रूप से सत्ता के

लिए संघर्ष है।

206. मध्यकालीन चिंतन में, 'रेग्नम' शब्द किसके अधिकार क्षेत्र को संदर्भित करता है?
(A) पुरोहितीय या आध्यात्मिक अधिकार।
(B) सांसारिक या शाही अधिकार।
(C) मठवासी जीवन।
(D) विद्वानों की बहस।

207. एक कम आय वाले क्षेत्र के लिए सार्वजनिक पुस्तकालय बनाम एक अमीर क्षेत्र के लिए सड़क मरम्मत के संबंध में बहस मौलिक रूप से किसके बारे में है?
(A) नकारात्मक स्वतंत्रता बनाम सकारात्मक स्वतंत्रता
(B) व्यक्तिगत न्याय बनाम सामाजिक न्याय
(C) प्रत्यक्ष लोकतंत्र बनाम प्रतिनिधि लोकतंत्र
(D) चर्च-राज्य संबंध

208. उत्तर-व्यवहारवाद में "प्रासंगिकता का सिद्धांत" क्या था?
(A) सामाजिक मुद्दों को हल करने के लिए राजनीति विज्ञान का आह्वान।
(B) यह विश्वास कि शोध केवल शोधकर्ता के लिए प्रासंगिक होना चाहिए।
(C) यह तर्क कि केवल ऐतिहासिक शोध ही प्रासंगिक है।
(D) सभी सैद्धांतिक प्रासंगिकता की अस्वीकृति।

209. एक विचारधारा अनुयायियों को पहचान की भावना प्रदान करती है। यह विचारधारा का _____ कार्य है।
(A) लामबंदी
(B) वैधीकरण
(C) सामाजिक
(D) व्याख्यात्मक

210. व्यवहारवाद के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करें:
I. इसने राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञानों के मॉडल पर ढाला।
II. इसने अवलोकनीय व्यवहार पर जोर दिया।
III. इसने मानकीय प्रश्नों को प्रधानता दी।
उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) केवल I और II
(B) केवल III
(C) केवल I और III
(D) I, II और III

211. लेनिन के अनुसार, क्रांति के बाद पार्टी की क्या भूमिका है?
(A) तुरंत खुद को भंग कर लेना।
(B) सभी दलों के गठबंधन को सत्ता सौंप देना।
(C) पार्टी के नियंत्रण में राजतंत्र को बहाल करना।
(D) "सर्वहारा की तानाशाही" स्थापित करना।

212. निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता और व्यवस्था के बीच संभावित संघर्ष का परिदृश्य है?
(A) दंगों को दबाने के लिए सरकार द्वारा सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध लगाना।
(B) प्रेस की स्वतंत्रता की गारंटी देने वाली सरकार।
(C) सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने वाली सरकार।
(D) स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने वाली सरकार।

213. दो तलवारों का जेलासियन सिद्धांत किसकी प्रतिक्रिया थी?
(A) एथेनियन लोकतंत्र के पतन की।
(B) सामंतवाद के उदय की।
(C) धर्मसुधार आंदोलन की।
(D) रोमन सम्राट में अधिकार के एकीकरण की।

214. "सामाजिक न्याय" की अवधारणा मुख्य रूप से किससे संबंधित है?
(A) व्यक्तिगत अदालती मामले।
(B) अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ।
(C) व्यक्तिगत संबंध।
(D) सामाजिक परिणाम और वितरण।

215. "राजनीतिक सिद्धांत के पतन" शोध प्रबंध विवादास्पद था क्योंकि इसने:
(A) इसे सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया था।
(B) एक प्रमुख अनुशासन शाखा के उद्देश्य को चुनौती दी।
(C) विश्वविद्यालयों को समाप्त करने का तर्क दिया।
(D) केवल अस्पष्ट पत्रिकाओं में प्रकाशित हुआ था।

216. गांधी के लिए, 'सत्याग्रह' किसका साधन था?
(A) बल प्रयोग के माध्यम से राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने का।
(B) एकांत में व्यक्तिगत ज्ञान प्राप्त करने का।
(C) सत्य और न्याय के लिए नैतिक संघर्ष करने का।
(D) चतुर बहस के माध्यम से तर्क जीतने का।

217. गलत युग्म की पहचान करें।
(A) व्यवहारवाद - मूल्य-मुक्त विश्लेषण
(B) उत्तर-व्यवहारवाद - प्रासंगिकता और कार्रवाई
(C) गांधीवादी सिद्धांत - अग्रगामी दल
(D) मध्यकालीन राजनीतिक चिंतन - दो तलवारों का सिद्धांत

218. माओ के परिवर्तन के सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण घटक "जन-लाइन" था। इसका अर्थ था:
(A) पार्टी को जनता के विचारों को संश्लेषित करना और समझाना चाहिए।
(B) पार्टी को बिना परामर्श के नीतियों को थोपना चाहिए।
(C) जनता को पार्टी नेतृत्व के बिना शासन करना चाहिए।
(D) पार्टी को विशिष्ट बुद्धिजीवियों पर निर्भर रहना चाहिए।

219. 'एक व्यक्ति, एक वोट' का सिद्धांत किसकी अभिव्यक्ति है?
(A) आर्थिक समानता
(B) सामाजिक समानता

Downloaded from www.pdf.tube

(C) कानूनी समानता
(D) राजनीतिक समानता

220. कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करें:
1. जेलासियन सिद्धांत।
2. व्यवहारवाद का उदय।
3. बोल्शेविक क्रांति।
4. रॉल्स की "थ्योरी ऑफ जस्टिस" का प्रकाशन।
(A) 1, 3, 2, 4
(B) 1, 2, 3, 4
(C) 2, 1, 4, 3
(D) 3, 1, 2, 4

221. एक विचारधारा को 'लेंस' के रूप में देखा जा सकता है। इसका अर्थ है:
(A) यह घटनाओं की धारणा और व्याख्या को आकार देती है।
(B) यह वास्तविकता को पूरी तरह विकृत कर देती है।
(C) यह वस्तुनिष्ठ अवलोकन का एक उपकरण है।
(D) हर कोई दुनिया को एक ही लेंस से देखता है।

222. "राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान" के समर्थकों ने तर्क दिया कि:
(A) सिद्धांत पहले कभी इतना जीवंत नहीं था।
(B) व्यवहारवाद ने सभी बड़े प्रश्नों के उत्तर दे दिए थे।
(C) 'बड़े प्रश्नों' पर फिर से रचनात्मक रूप से बहस की जा रही थी।
(D) इतिहास का अध्ययन अब आवश्यक नहीं था।

223. सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता के बीच मुख्य अंतर क्या है?
(A) नकारात्मक 'से स्वतंत्रता' है; सकारात्मक 'की स्वतंत्रता' है।
(B) नकारात्मक 'की स्वतंत्रता' है; सकारात्मक 'से स्वतंत्रता' है।
(C) नकारात्मक समूहों पर लागू होती है; सकारात्मक व्यक्तियों पर।
(D) नकारात्मक दार्शनिक है; सकारात्मक कानूनी है।

224. मध्यकालीन चर्च-राज्य संबंधों में, 'आध्यात्मिक तलवार' किसके पास थी?
(A) पोप और चर्च पदानुक्रम
(B) राजा या सम्राट
(C) सामंती प्रभुओं
(D) आम जनता

225. विश्वविद्यालय प्रवेश में सकारात्मक कार्रवाई किसका व्यावहारिक अनुप्रयोग है?
(A) केवल योग्यता पर आधारित व्यक्तिगत न्याय।
(B) नकारात्मक स्वतंत्रता।
(C) केवल प्रक्रियात्मक न्याय।
(D) पिछले भेदभाव के लिए सामाजिक न्याय।

226. लेनिन ने तर्क दिया कि क्रांति उस देश में हो सकती है जो:
(A) पूरी तरह से विकसित पूंजीवादी था।
(B) औद्योगिक सर्वहारा वर्ग के बिना था।
(C) बिना किसी पूंजीवाद के सामंती था।
(D) पूंजीवादी श्रृंखला की "सबसे कमजोर कड़ी" था।

227. कौन सा कथन उत्तर-व्यवहारवादी स्थिति का सबसे अच्छा सारांश प्रस्तुत करता है?
(A) "तथ्यों और मूल्यों को अलग रखा जाना चाहिए।"
(B) "जानना कार्य करने की जिम्मेदारी लेना है।"
(C) "केवल तकनीकी कठोरता ही मायने रखती है।"
(D) "राजनीति के अध्ययन को त्याग दिया जाना चाहिए।"

228. लोकतंत्र की अवधारणा किसके प्रति प्रतिबद्धता दर्शाती है?
(A) एक विशिष्ट आर्थिक प्रणाली।
(B) निर्णय लेने की प्रक्रियाओं का एक समूह।
(C) एक विशेष धार्मिक विश्वास।
(D) सरकार का एक ही रूप।

229. निम्नलिखित में से कौन गांधीवादी चिंतन का मूल तत्व नहीं है?
(A) सत्याग्रह
(B) अहिंसा
(C) सर्वोदय
(D) इतिहास के प्राथमिक चालक के रूप में वर्ग संघर्ष

230. "राजनीतिक सिद्धांत के पतन" ने सुझाव दिया कि सिद्धांत व्यवहारवाद और किसके द्वारा दबाया गया था?
(A) अराजकतावाद
(B) साम्यवाद
(C) इतिहासवाद
(D) आदर्शवाद

231. अवसर की समानता के पीछे मूल विचार क्या बनाना है?
(A) ऐसा समाज जहाँ सबकी आय समान हो।
(B) ऐसी प्रणाली जहाँ सरकार सभी निर्णय लेती है।
(C) सामाजिक प्रतिस्पर्धा के लिए एक "समान अवसर का मैदान"।
(D) कानूनों या सरकार के बिना समाज।

232. मध्यकालीन राजनीतिक चिंतन में, सत्ता के लिए अंतिम औचित्य किससे आता था?
(A) जनता से
(B) ईश्वर से
(C) सैन्य शक्ति से
(D) तर्कसंगत सहमति से

233. एक विचारधारा का मुख्य कार्य क्या है?
(A) विश्वासों को प्राकृतिक और निर्विवाद रूप में प्रस्तुत

करना।
(B) नागरिकों को भ्रमित और विचलित करना।
(C) आलोचनात्मक स्वतंत्र सोच को प्रोत्साहित करना।
(D) विशुद्ध वैज्ञानिक विश्लेषण प्रदान करना।

234. माओ का सिद्धांत शास्त्रीय मार्क्सवाद से अलग है क्योंकि यह:
(A) वर्ग संघर्ष को पूरी तरह से खारिज करता है।
(B) शांतिपूर्ण संक्रमण की वकालत करता है।
(C) पूंजीवादी शक्तियों के साथ गठबंधन का आह्वान करता है।
(D) किसान वर्ग को मुख्य शक्ति के रूप में पहचानता है।

235. "व्यक्तिगत न्याय" की अवधारणा किस राजनीतिक विचारधारा से निकटता से जुड़ी है?
(A) उदारवाद
(B) साम्यवाद
(C) फासीवाद
(D) अराजकतावाद

236. डेविड ईस्टन का व्यवहारवाद से उत्तर-व्यवहारवाद की ओर झुकाव क्या दर्शाता है?
(A) पहले के काम की पूर्ण अस्वीकृति।
(B) मूल्य-मुक्त दृष्टिकोण की सीमाओं की मान्यता।
(C) पारंपरिक ऐतिहासिक विधियों में परिवर्तन।
(D) राजनीति के लिए शिक्षा जगत छोड़ने का निर्णय।

237. गणतंत्र की सामान्य समझ क्या है?
(A) एक राजा द्वारा शासित प्रणाली।
(B) केवल एक द्वि-दलीय प्रणाली।
(C) लोकतंत्र से कोई अंतर नहीं है।
(D) सुरक्षा उपायों के साथ एक प्रतिनिधि प्रणाली।

238. "प्रत्येक से उसकी क्षमता के अनुसार, प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार" किसे प्राथमिकता देता है?
(A) नकारात्मक स्वतंत्रता
(B) अवसर की समानता
(C) परिणाम की समानता
(D) प्रक्रियात्मक न्याय

239. "क्या किया जाना चाहिए?" का केंद्रीय विषय किसकी आवश्यकता है?
(A) सामाजिक वर्गों का एक व्यापक गठबंधन।
(B) नेतृत्व के बिना स्वतःस्फूर्त विद्रोह।
(C) पेशेवर क्रांतिकारियों की एक पार्टी।
(D) संसद के माध्यम से क्रमिक सुधार।

240. अवधारणा को उसके सर्वोत्तम उदाहरण के साथ सुमेलित करें।
सूची I: (अवधारणा)
P. सामाजिक न्याय
Q. नकारात्मक स्वतंत्रता
R. प्रक्रियात्मक लोकतंत्र
S. गांधीवादी सत्याग्रह
सूची II: (उदाहरण)
1. सेंसरशिप को रद्द करना
2. बहुदलीय चुनाव
3. दांडी यात्रा
4. सकारात्मक कार्रवाई
(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-4, Q-1, R-2, S-3
(C) P-4, Q-2, R-1, S-3
(D) P-2, Q-1, R-4, S-3

241. नियुक्ति को लेकर संघर्ष किस पर संघर्ष की अभिव्यक्ति थी?
(A) लोकप्रिय संप्रभुता
(B) दो तलवारों का सिद्धांत
(C) सामंती आर्थिक संबंध
(D) राष्ट्रवाद का उदय

242. उत्तर-व्यवहारवाद तर्क देता है कि तथ्य और मूल्य हैं:
(A) एक ही बात।
(B) इन्हें पूरी तरह अलग रखना सबसे अच्छा है।
(C) आपस में जुड़े हुए और गैर-तटस्थ।
(D) राजनीति के अध्ययन के लिए अप्रासंगिक।

243. "राजनीतिक सिद्धांत का पुनरुत्थान" किस पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने से जुड़ा है?
(A) चुनावी सांख्यिकी
(B) न्याय जैसे महान मानकीय विषय।
(C) प्रशासनिक राज्य
(D) नेताओं की मनोवैज्ञानिक रूपरेखा

244. लेनिन और गांधी के बीच सबसे महत्वपूर्ण अंतर किसमें निहित है?
(A) नेतृत्व की भूमिका
(B) हिंसा की आवश्यकता और नैतिकता
(C) जनता का महत्व
(D) आर्थिक परिवर्तन की आवश्यकता

245. मनमानी गिरफ्तारी से मुक्त होने का व्यक्ति का अधिकार किसका एक उदाहरण है?
(A) सकारात्मक स्वतंत्रता
(B) सामाजिक न्याय
(C) नकारात्मक स्वतंत्रता
(D) परिणाम की समानता

246. विचारधारा के 'कार्रवाई के कार्यक्रम' का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?
(A) ऐतिहासिक वृत्तांत प्रदान करना।
(B) वांछित समाज प्राप्त करने के लिए चरणों की रूपरेखा तैयार करना।
(C) एक जटिल दार्शनिक आलोचना प्रस्तुत करना।

Click Here to Buy book on Amazon

(D) यह सुनिश्चित करना कि विचारधारा सैद्धांतिक बनी रहे।

247. 'वितरणात्मक न्याय' की अवधारणा किसका एक प्रमुख घटक है?
(A) व्यक्तिगत न्याय
(B) सामाजिक न्याय
(C) प्रतिशोधक न्याय
(D) औपचारिक न्याय

248. चीन के लिए मार्क्सवाद-लेनिनवाद का माओ द्वारा अनुकूलन किसका एक उदाहरण है?
(A) एकल मॉडल की सार्वभौमिक स्वीकार्यता।
(B) विशिष्ट राष्ट्रीय स्थितियों के अनुसार विचारधारा को ढालना।
(C) सभी मार्क्सवादी सिद्धांतों की अस्वीकृति।
(D) शहरी नेतृत्व वाली क्रांति के लिए प्राथमिकता।

249. कौन सा कथन प्रक्रियात्मक और सारवान लोकतंत्र के बीच संबंध का सही वर्णन करता है?
(A) एक राज्य में सारवान लोकतंत्र के बिना प्रक्रियात्मक लोकतंत्र हो सकता है।
(B) एक राज्य में प्रक्रियात्मक लोकतंत्र के बिना सारवान लोकतंत्र हो सकता है।
(C) दोनों अवधारणाएं समान हैं।
(D) प्रक्रियात्मक लोकतंत्र केवल राजतंत्रों के लिए है।

250. निम्नलिखित अभिकथन (A) और कारण (R) पर विचार करें।
अभिकथन (A): माओ के परिवर्तन के सिद्धांत में, किसान वर्ग अग्रणी भूमिका निभाता है।
कारण (R): माओ का मानना था कि किसान वर्ग चीन में सबसे संख्यात्मक और उत्पीड़ित वर्ग था।
(A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(D) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

251. व्यवहारवाद की एक प्रमुख विशेषता 'व्यवस्थित' होना था, जो किस पर जोर देती थी?
(A) समग्र रूप से राजनीतिक प्रणालियों का अध्ययन।
(B) दिलचस्प तथ्यों का यादृच्छिक संग्रह।
(C) सिद्धांत और शोध के बीच संबंध।
(D) व्यक्तिगत केस अध्ययन।

252. "क्रिश्चियनडम" का मध्यकालीन आदर्श किसके उदय के साथ समाप्त हो गया?
(A) व्यवहारवादी आंदोलन
(B) केंद्रीकृत राजतंत्र और संप्रभु राज्य
(C) दो तलवारों का सिद्धांत
(D) विश्वविद्यालय प्रणाली

253. 'सकारात्मक स्वतंत्रता' की अवधारणा को इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है:
(A) सभी नियमों का अभाव।
(B) अपनी क्षमता को साकार करने की स्वतंत्रता।
(C) केवल सकारात्मक मनःस्थिति में प्राप्त स्वतंत्रता।
(D) हस्तक्षेप न किए जाने का अधिकार।

254. साध्य और साधन के संबंध में गांधी का सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है?
(A) साध्य साधनों का औचित्य सिद्ध करते हैं।
(B) साधनों और साध्य की शुद्धता।
(C) अग्रगामी दल का सिद्धांत।
(D) अंतर्विरोधों का सिद्धांत।

255. सामाजिक न्याय मौलिक रूप से इस विचार की आलोचना है कि:
(A) समाज निष्पक्ष होना चाहिए।
(B) केवल व्यक्तिगत योग्यता ही किसी की नियति निर्धारित करती है।
(C) अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका है।
(D) लोगों के पास समान अधिकार होने चाहिए।

256. लेनिन के पार्टी सिद्धांत की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है?
(A) लोकतांत्रिक केंद्रीयवाद
(B) खुली और समावेशी सदस्यता
(C) स्वतःस्फूर्त संगठन
(D) सभी पदानुक्रमों की अस्वीकृति

257. 'विचारधारावादी' वह व्यक्ति है जो:
(A) सभी राजनीतिक विश्वासों के प्रति संशयवादी है।
(B) किसी विशेष विचारधारा का मजबूती से पालन करता है और उसे आगे बढ़ाता है।
(C) विचारधाराओं का तटस्थ दृष्टिकोण से अध्ययन करता है।
(D) जिसकी कोई राजनीतिक राय नहीं है।

258. राजनीतिक सिद्धांत के 'पुनरुत्थान' ने किसकी विफलता पर प्रतिक्रिया व्यक्त की?
(A) 1960 के दशक की उथल-पुथल की भविष्यवाणी करने में।
(B) जटिल सांख्यिकीय मॉडल विकसित करने में।
(C) गैर-पश्चिमी देशों की राजनीति का अध्ययन करने में।
(D) शक्ति की एकल परिभाषा बनाने में।

259. राजनीतिक समानता का अर्थ है:
(A) सभी नागरिकों के पास समान संपत्ति है।
(B) निर्णय लेने में सभी नागरिकों का समान महत्व है।
(C) सभी राजनीतिक राय समान रूप से मान्य हैं।
(D) सभी राजनेता शक्ति में समान हैं।

Downloaded from www.pdf.tube

260. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
I. कानूनी समानता का अर्थ है कानून सभी पर समान रूप से लागू होता है।
II. अवसर की समानता का अर्थ है योग्यता के लिए बाधाओं को दूर करना।
III. परिणाम की समानता संसाधन विषमताओं को कम करने का प्रयास करती है।
उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) केवल I
(B) केवल I और II
(C) केवल II और III
(D) I, II और III

261. दो तलवारों का सिद्धांत किस दौरान सबसे अधिक प्रासंगिक था?
(A) शास्त्रीय पुरातन काल
(B) यूरोपीय मध्यकाल
(C) पुनर्जागरण
(D) प्रबोधन काल

262. निम्नलिखित में से कौन व्यवहारवाद की उत्तर-व्यवहारवादी आलोचना का प्रतिनिधित्व करता है?
(A) यह पर्याप्त वैज्ञानिक नहीं था।
(B) मूल्य-तटस्थता के कारण यथास्थिति का बचाव हुआ।
(C) यह प्रासंगिकता पर बहुत अधिक केंद्रित था।
(D) यह ऐतिहासिक ग्रंथों पर बहुत अधिक निर्भर था।

263. गांधीवादी 'न्यासधारिता' की अवधारणा किसके बारे में एक सिद्धांत है?
(A) राजनीतिक शक्ति
(B) संपत्ति और धन
(C) धार्मिक अधिकार
(D) अंतर्राष्ट्रीय संबंध

264. 'सामाजिक न्याय' की चिंता का प्राथमिक विषय क्या है?
(A) व्यक्तिगत आपराधिक व्यवहार।
(B) सामाजिक संस्थानों की बुनियादी संरचना।
(C) संचार का शिष्टाचार।
(D) एकल लेनदेन की निष्पक्षता।

265. समाजवाद के तहत माओ की "स्थायी क्रांति" की अवधारणा को क्या अलग करता है?
(A) सत्ता पर कब्जे के बाद वर्ग संघर्ष समाप्त हो जाता है।
(B) कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर ही वर्ग संघर्ष जारी रहता है।
(C) क्रांति का अन्य देशों में लगातार विस्तार करना।
(D) राजनीति के बजाय आर्थिक विकास पर ध्यान देना।

266. ऐसी सरकार जहाँ स्वतंत्र चुनाव होते हैं लेकिन प्रतिनिधियों के पास बहुत कम शक्ति होती है, वहाँ है:
(A) मजबूत प्रक्रियात्मक लेकिन कमजोर सारवान लोकतंत्र।
(B) कमजोर प्रक्रियात्मक लेकिन मजबूत सारवान लोकतंत्र।
(C) मजबूत प्रत्यक्ष लोकतंत्र।
(D) कोई लोकतंत्र नहीं।

267. राजनीतिक सिद्धांत के "पतन" पर उन लोगों ने शोक व्यक्त किया जिन्हें लगा कि यह अपना क्या खो रहा है:
(A) सांख्यिकीय परिष्कार।
(B) अपनी शास्त्रीय विरासत के साथ संबंध।
(C) सरकारी स्रोतों से धन।
(D) जनमत सर्वेक्षण करने की क्षमता।

268. विचारधारा का एक मुख्य घटक 'अच्छे समाज' का उसका दृष्टिकोण है जो किस कार्य के लिए है:
(A) राजनीतिक कार्रवाई के लिए लक्ष्य प्रदान करना।
(B) यह सिद्ध करना कि वर्तमान समाज उत्तम है।
(C) भ्रम और उदासीनता पैदा करना।
(D) एक वैज्ञानिक परीक्षण योग्य परिकल्पना प्रस्तुत करना।

269. सभी नागरिकों के लिए मतदान अनिवार्य करने वाला कानून संभवतः किसका उल्लंघन करता है?
(A) सकारात्मक स्वतंत्रता
(B) नकारात्मक स्वतंत्रता
(C) सामूहिक स्वतंत्रता
(D) आर्थिक स्वतंत्रता

270. लेनिन के सिद्धांत में, "अग्रगामी" पार्टी किससे बनी होनी चाहिए?
(A) संपूर्ण श्रमिक वर्ग से।
(B) समर्पित पेशेवर क्रांतिकारियों से।
(C) बुर्जुआ वर्ग के बुद्धिजीवियों से।
(D) विशेष रूप से किसानों और खेतिहरों से।

271. बोनिफेस VIII और फिलिप IV के बीच संघर्ष किसके ऊपर संघर्ष का एक उदाहरण था?
(A) दो तलवारों का सिद्धांत
(B) व्यवहारवाद
(C) गांधीवादी सत्याग्रह
(D) राजनीतिक सिद्धांत का पतन

272. व्यवहारवाद का मुख्य केंद्र क्या है?
(A) संविधानों का पाठ।
(B) राजनीति में व्यक्तियों का अवलोकनीय व्यवहार।
(C) महान राजनेताओं का जीवन।
(D) राज्य के दार्शनिक औचित्य।

273. 'व्यक्तिगत न्याय' की अवधारणा मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है?
(A) धन का पुनर्वितरण।
(B) कानूनी प्रणाली के भीतर अधिकार और निष्पक्ष व्यवहार।
(C) समुदाय का समग्र कल्याण।
(D) समूहों के विरुद्ध ऐतिहासिक गलतियों को सुधारना।

NODIA

274. जॉन रॉल्स ने क्या प्रयास किया?
(A) विशुद्ध रूप से उदारवादी राज्य का औचित्य सिद्ध करना।
(B) एक न्यायपूर्ण उदार समाज के लिए आधार प्रदान करना।
(C) यह सिद्ध करना कि न्याय एक अप्रासंगिक अवधारणा है।
(D) मध्यकालीन सरकार की ओर लौटने का तर्क देना।

275. वर्ग संघर्ष के विपरीत, गांधी ने किस पर ध्यान केंद्रित किया?
(A) मानवता की एकता और नैतिक अनुनय।
(B) एक नस्लीय युद्ध।
(C) औद्योगिक अभिजात वर्ग का नेतृत्व।
(D) हिंसक संघर्ष की अपरिहार्यता।

276. कौन सी नीति अवसर की समानता को बढ़ावा देती है?
(A) सभी निजी संपत्ति को जब्त करना।
(B) प्रत्येक नागरिक को समान आय की गारंटी देना।
(C) सभी बच्चों को मुफ्त सार्वजनिक शिक्षा प्रदान करना।
(D) सभी कानूनों को समाप्त करना।

277. "विचारधारा" शब्द का मूल रूप से था:
(A) विचारों के विज्ञान के रूप में सकारात्मक अर्थ।
(B) अमूर्त विश्वासों के रूप में नकारात्मक अर्थ।
(C) कीटों के संबंध में तटस्थ अर्थ।
(D) अलग-अलग समय पर सकारात्मक और नकारात्मक अर्थ।

278. "सांस्कृतिक क्रांति" माओ द्वारा किसके लिए शुरू की गई थी?
(A) आर्थिक विकास और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए।
(B) संशोधनवाद से लड़ने और अपने दृष्टिकोण को फिर से स्थापित करने के लिए।
(C) बहुदलीय लोकतांत्रिक सुधारों को पेश करने के लिए।
(D) सोवियत संघ के साथ संबंधों को बढ़ावा देने के लिए।

279. उत्तर-व्यवहारवाद में 'प्रासंगिकता' की मांग का अर्थ था कि वैज्ञानिकों को:
(A) समकालीन समस्याओं से बचना चाहिए।
(B) दबावपूर्ण मुद्दों के साथ जुड़ना और उन्हें हल करना चाहिए।
(C) केवल अमूर्त मॉडलों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
(D) केवल व्यक्तिगत रूप से प्रासंगिक विषयों का अध्ययन करना चाहिए।

280. लोकप्रिय संप्रभुता का अर्थ है कि अंतिम राजनीतिक अधिकार किसमें निहित है:
(A) सम्राट में।
(B) जनता में।
(C) न्यायपालिका में।
(D) संप्रभु राज्य में।

281. "दो तलवारें" स्थिर विभाजन बनाने में विफल रहीं क्योंकि:
(A) बारूद ने तलवारों को अप्रचलित कर दिया।
(B) दावों में अतिव्याप्ति हुई, जिससे संघर्ष हुआ।
(C) जनता ने रूपक को अस्वीकार कर दिया।
(D) सामंती प्रभुओं ने अधिकार से इनकार कर दिया।

282. कौन सा सिद्धांत व्यक्तियों को बदलने और वैकल्पिक विकेंद्रीकृत संस्थानों पर ध्यान केंद्रित करता है?
(A) लेनिनवादी सिद्धांत
(B) माओवादी सिद्धांत
(C) गांधीवादी सिद्धांत
(D) व्यवहारवादी सिद्धांत

283. कुछ सिद्धांतों में, एक 'अधिकार' 'स्वतंत्रता' से भिन्न होता है क्योंकि:
(A) कोई अंतर नहीं है।
(B) एक अधिकार किसी और पर कर्तव्य थोपता है।
(C) एक स्वतंत्रता किसी और पर कर्तव्य थोपती है।
(D) अधिकार कानूनी हैं; स्वतंत्रता दार्शनिक है।

284. तार्किक प्रत्यक्षवाद का मानना था कि:
(A) ज्ञान रहस्योद्घाटन से आता है।
(B) जो कथन अनुभवजन्य रूप से सत्यापन योग्य नहीं हैं, वे अर्थहीन हैं।
(C) ऐतिहासिक अध्ययन उच्चतम ज्ञान है।
(D) मूल्य तथ्यों से अधिक महत्वपूर्ण हैं।

285. 'लामबंदी' का अर्थ है कि एक विचारधारा कर सकती है:
(A) लोगों को निष्क्रिय बनाना।
(B) लोगों को सामूहिक कार्रवाई करने के लिए राजी करना।
(C) केवल अभिजात वर्ग द्वारा समझा जाना।
(D) सेना को विखंडित करने के लिए उपयोग किया जाना।

286. सामाजिक न्याय का मौलिक लक्ष्य क्या है?
(A) यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक व्यक्ति को वह मिले जो वह चाहता है।
(B) लाभों और बोझों का उचित वितरण करना।
(C) असहमति के सभी रूपों को दंडित करना।
(D) मौजूदा सामाजिक पदानुक्रम को बनाए रखना।

287. माओ के "जनयुद्ध" का अंतिम चरण है:
(A) रणनीतिक रक्षात्मक
(B) रणनीतिक गतिरोध
(C) रणनीतिक आक्रामक
(D) रणनीतिक पीछे हटना

288. सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंधित करना किसके बीच संघर्ष के रूप में देखा जा सकता है?
(A) नकारात्मक स्वतंत्रता और सार्वजनिक कल्याण।
(B) सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता।
(C) सामाजिक और व्यक्तिगत न्याय।
(D) लोकतंत्र और राजतंत्र।

Click Here to Buy book on Amazon

289. "लौकिक तलवार" किसका प्रतीक थी?
(A) बहिष्कृत करने की चर्च की शक्ति।
(B) शासन करने और युद्ध करने की धर्मनिरपेक्ष शक्ति।
(C) विश्वविद्यालयों का बौद्धिक अधिकार।
(D) श्रेणियों की आर्थिक शक्ति।

290. उत्तर-व्यवहारवाद के "कार्रवाई" पर जोर देने ने किसके कर्तव्य का सुझाव दिया?
(A) मुद्दों पर मौन रहना।
(B) समाज को बेहतर बनाने के लिए ज्ञान का उपयोग करना।
(C) सैद्धांतिक कार्य पर ध्यान केंद्रित करना।
(D) सार्वजनिक पद के लिए चुनाव लड़ना।

291. लेनिन ने तर्क दिया कि बुर्जुआ राज्य को:
(A) धीरे-धीरे सुधारा जाना चाहिए।
(B) कब्जा करके उपयोग किया जाना चाहिए।
(C) नष्ट करके प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए।
(D) अनदेखा किया जाना चाहिए।

292. स्वतंत्र प्रेस और विपक्षी दल किसके संकेतक हैं?
(A) एक स्वस्थ प्रक्रियात्मक लोकतंत्र।
(B) एक कमान अर्थव्यवस्था।
(C) एक धर्मतंत्रीय राज्य।
(D) राजनीतिक सिद्धांत का पतन।

293. निम्नलिखित में से कौन गांधी के विचार का मूल घटक नहीं है?
(A) स्वराज
(B) सर्वोदय
(C) इतिहास के चालक के रूप में वर्ग संघर्ष
(D) अहिंसा

294. "कानून के समक्ष समानता" किस परंपरा की आधारशिला है?
(A) फासीवाद
(B) साम्यवाद
(C) उदार-संवैधानिकवाद
(D) धर्मतंत्र

295. "राजनीतिक सिद्धांत का पुनरुत्थान" किसके द्वारा चिह्नित किया गया था?
(A) सभी बहसों का अंत।
(B) मानकीय प्रश्नों में नए सिरे से विश्वास।
(C) एकल शोध पद्धति को अपनाना।
(D) राजनीति विज्ञान की अस्वीकृति।

296. "अंतर्विरोध पर" का केंद्रीय तर्क यह है कि:
(A) सभी अंतर्विरोध समान महत्व के होते हैं।
(B) एक मुख्य अंतर्विरोध प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाता है।
(C) समाज अंतर्विरोधों के बिना अस्तित्व में रह सकता है।
(D) अंतर्विरोधों की अनदेखी की जानी चाहिए।

297. एक राजनीतिक उपकरण के रूप में बहिष्करण ने क्या प्रदर्शित किया?
(A) चर्च के पास शक्ति की कमी।
(B) आध्यात्मिक और लौकिक अधिकार का आपस में जुड़ा होना।
(C) चर्च और राज्य का पूर्ण पृथक्करण।
(D) विशुद्ध आर्थिक मामलों पर ध्यान।

298. तथ्य-मूल्य द्विभाजन बताता है कि:
(A) तथ्य और मूल्य एक ही हैं।
(B) कोई 'है' से 'होना चाहिए' प्राप्त कर सकता है।
(C) कोई तथ्य से मूल्य प्राप्त नहीं कर सकता।
(D) सभी तथ्य मूल्य-युक्त होते हैं।

299. सामाजिक न्याय किस प्रश्न से सबसे अधिक संबंधित है?
(A) क्या अभियुक्त को निष्पक्ष सुनवाई मिली?
(B) क्या समूहों में अवसरों का वितरण निष्पक्ष है?
(C) क्या अनुबंध दबाव में हस्ताक्षरित किया गया था?
(D) क्या राजा को युद्ध घोषित करने का अधिकार है?

300. लेनिन और गांधी के बीच जन लामबंदी में मुख्य अंतर क्या है?
(A) लेनिन ने किसान वर्ग पर ध्यान केंद्रित किया।
(B) लेनिन ने हिंसक कब्जे की मांग की; गांधी ने अहिंसा की मांग की।
(C) गांधी अग्रगामी दल में विश्वास करते थे।
(D) कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं था।

NODIA

उत्तर (व्याख्या सहित)

1. (B) दो तलवारों का सिद्धांत
मध्यकालीन राजनीतिक चिंतन में चर्च और राज्य के संबंधों को स्पष्ट करने हेतु दो तलवारों का सिद्धांत अत्यधिक महत्वपूर्ण था। इस अवधारणा के अनुसार, ईश्वर ने संसार के शासन हेतु दो पृथक शक्तियाँ प्रदान की हैं। आध्यात्मिक तलवार चर्च के पास होती है, जबकि लौकिक तलवार धर्मनिरपेक्ष शासक के पास होती है। यह सिद्धांत दोनों सत्ताओं के अधिकार क्षेत्रों के विभाजन और उनके मध्य होने वाले संघर्ष तथा संतुलन को दर्शाता है।

2. (A) यह व्यक्तियों के प्रत्यक्ष कार्यों के माध्यम से राजनीतिक गतिविधि की व्याख्या करता है।
राजनीति विज्ञान में व्यवहारवादी दृष्टिकोण राजनीतिक गतिविधियों को समझने हेतु व्यक्तियों और समूहों के प्रत्यक्ष कार्यों तथा व्यवहार पर केंद्रित है। यह औपचारिक संस्थागत संरचनाओं के स्थान पर मानव व्यवहार के अनुभवजन्य और वैज्ञानिक अध्ययन को प्राथमिकता देता है। इसका मुख्य उद्देश्य संकलित आँकड़ों के माध्यम से राजनीतिक प्रक्रियाओं में नियमितताओं की खोज करना है। यह दृष्टिकोण राजनीति विज्ञान को अधिक वैज्ञानिक और तथ्य-आधारित बनाने का प्रयास करता है।

3. (A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।
लोकतंत्र को दो प्रमुख दृष्टिकोणों से समझा जा सकता है। प्रक्रियात्मक लोकतंत्र मुख्य रूप से शासन की प्रणालियों और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव जैसी विधियों पर ध्यान केंद्रित करता है। इसके विपरीत, सारवान लोकतंत्र शासन के वास्तविक परिणामों और समाज में समानता एवं न्याय की प्राप्ति की सीमा पर बल देता है। ये दोनों अवधारणाएं परस्पर पूरक हैं, जहाँ चुनावी प्रक्रियाओं की शुद्धता और सामाजिक-आर्थिक न्याय का लक्ष्य दोनों ही अनिवार्य हैं।

4. (D) बाहरी बाधाओं या दूसरों द्वारा हस्तक्षेप से मुक्ति।
नकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा व्यक्ति के लिए ऐसे कार्यक्षेत्र की वकालत करती है जहाँ वह दूसरों के हस्तक्षेप के बिना निर्णय ले सके। इसमें स्वतंत्रता को बाहरी बाधाओं की अनुपस्थिति के रूप में देखा जाता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार, राज्य या अन्य व्यक्तियों का न्यूनतम हस्तक्षेप व्यक्ति की स्वायत्तता को सुरक्षित रखता है। यह विचारधारा व्यक्तिवादी सिद्धांतों पर आधारित है और मानती है कि कानून केवल अधिकारों के उल्लंघन पर हस्तक्षेप करे।

5. (A) P-4, Q-1, R-2, S-3
विभिन्न राजनीतिक विचारकों ने सामाजिक परिवर्तन के लिए विशिष्ट अवधारणाएं प्रस्तुत की हैं। लेनिन ने क्रांति के सफल संचालन हेतु एक अनुशासित अग्रगामी दल की भूमिका को अनिवार्य माना। माओ जेदोंग ने ग्रामीण आधार क्षेत्रों के माध्यम से लंबी अवधि के जनयुद्ध की रणनीति अपनाई। महात्मा गांधी का परिवर्तन का सिद्धांत सत्याग्रह और अहिंसक प्रतिरोध पर आधारित है। वहीं कार्ल मार्क्स ने ऐतिहासिक भौतिकवाद के अंतर्गत पूंजीवाद के पश्चात सर्वहारा की तानाशाही का वर्णन किया है।

6. (B) सामाजिक न्याय
सार्वजनिक भवनों को दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुलभ बनाना सामाजिक न्याय की अवधारणा का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। सामाजिक न्याय समाज के सभी वर्गों, विशेषकर वंचितों और शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को समान अवसर प्रदान करने पर बल देता है। यह सिद्धांत केवल औपचारिक समानता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उन बाधाओं को दूर करने का प्रयास करता है जो किसी विशेष समूह के पूर्ण विकास में बाधक होती हैं। इससे समावेशी समाज बनता है।

7. (D) मानकीय और दार्शनिक जांच की प्रधानता।
व्यवहारवादी दृष्टिकोण की मुख्य विशेषता अनुभवजन्य और मात्रात्मक आँकड़ों पर ध्यान केंद्रित करना है। यह तथ्यों को नैतिक मूल्यों और मानकीय प्रश्नों से अलग रखने पर बल देता है। इसके अंतर्गत राजनीति विज्ञान को अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ एकीकृत कर एक वैज्ञानिक आधार प्रदान करने का प्रयास किया जाता है। मानकीय और दार्शनिक जांच को प्राथमिकता देना पारंपरिक दृष्टिकोण का हिस्सा है, जबकि व्यवहारवाद केवल अवलोकनीय और सत्यापन योग्य व्यवहार के अध्ययन को ही उचित मानता है।

8. (A) पोपतंत्र और राजतंत्र
मध्यकाल में प्रतिपादित दो तलवारों का सिद्धांत मुख्य रूप से पोपतंत्र और राजतंत्र के बीच अधिकार विभाजन से संबंधित था। इसमें यह तर्क दिया गया कि आध्यात्मिक सत्ता का प्रतिनिधित्व पोप करते हैं और लौकिक सत्ता का प्रतिनिधित्व सम्राट या राजा करते हैं। यह सिद्धांत दोनों संस्थाओं के स्वतंत्र कार्यक्षेत्रों को परिभाषित करने के लिए विकसित किया गया था, परंतु व्यवहार में इसने अक्सर दोनों शक्तियों के बीच प्रभुत्व को लेकर तीखे विवादों और राजनीतिक संघर्षों को जन्म दिया था।

9. (C) कृत्रिम बाधाओं को दूर करना ताकि सभी को समान अवसर मिल सके।
अवसर की समानता का सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि समाज के सभी व्यक्तियों को अपनी प्रतिभा और क्षमताओं के अनुसार विकास के समान अवसर प्राप्त हों। इसका प्राथमिक उद्देश्य उन कृत्रिम बाधाओं, जैसे जाति, लिंग या सामाजिक वर्ग को समाप्त करना है जो व्यक्ति की प्रगति में रुकावट पैदा करती

Downloaded from www.pdf.tube

हैं। यह अवधारणा परिणामों की पूर्ण समानता की गारंटी नहीं देती, बल्कि एक समान प्रतिस्पर्धात्मक आधार प्रदान करती है, जहाँ सफलता व्यक्ति के अपने प्रयासों पर निर्भर करती है।

10. (A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
उत्तर-व्यवहारवाद वास्तव में व्यवहारवादी क्रांति की उन कमियों के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया थी जिन्होंने तथ्यों पर अत्यधिक बल देकर मूल्यों की उपेक्षा की थी। उत्तर-व्यवहारवादियों ने तर्क दिया कि राजनीति विज्ञान के शोध को केवल वैज्ञानिक नहीं, बल्कि सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए प्रासंगिक भी होना चाहिए। उन्होंने माना कि ज्ञान का उद्देश्य समाज को बदलना और मानवता की सेवा करना है, जिसमें मूल्यों का समावेश अनिवार्य है। अतः यह दृष्टिकोण शोध की प्रासंगिकता पर बल देता है।

11. (D) राज्य के विरुद्ध क्रांति में सर्वहारा वर्ग का नेतृत्व करना।
लेनिन के अनुसार, अग्रगामी दल पेशेवर क्रांतिकारियों का एक अनुशासित और संगठित समूह है जिसका मुख्य कार्य सर्वहारा वर्ग को राजनीतिक चेतना प्रदान करना है। लेनिन का मानना था कि श्रमिक वर्ग स्वयं केवल आर्थिक चेतना विकसित कर सकता है, इसलिए उन्हें क्रांति की दिशा में प्रेरित करने के लिए कुशल नेतृत्व की आवश्यकता होती है। यह दल राज्य सत्ता पर कब्जा करने और समाजवाद की स्थापना के लिए सर्वहारा वर्ग को संगठित कर क्रांतिकारी संघर्ष का नेतृत्व करता है।

12. (B) प्रक्रियात्मक न्याय - परिणामों पर प्राथमिक ध्यान
प्रक्रियात्मक न्याय मुख्य रुप से उन विधियों और नियमों की निष्पक्षता से संबंधित है जिनके द्वारा निर्णय लिए जाते हैं। इसका मुख्य बल इस बात पर होता है कि प्रक्रिया न्यायसंगत होनी चाहिए, न कि अंतिम परिणाम पर। परिणामों पर प्राथमिक ध्यान देना सारवान न्याय या वितरणात्मक न्याय की विशेषता है। अन्य युग्म जैसे सामाजिक न्याय संसाधनों के उचित वितरण से और व्यक्तिगत न्याय कानून की उचित प्रक्रिया से सही ढंग से सुमेलित हैं। अतः प्रक्रियात्मक न्याय का संबंध प्रक्रिया की शुद्धता से है।

13. (C) इतिहासवाद और प्रत्यक्षवाद
बीसवीं शताब्दी के मध्य में कई विद्वानों ने राजनीतिक सिद्धांत के पतन की घोषणा की। इस पतन के लिए मुख्य रुप से इतिहासवाद और प्रत्यक्षवाद के उदय को जिम्मेदार ठहराया गया। इतिहासवाद ने सिद्धांतों को केवल उनके ऐतिहासिक संदर्भ तक सीमित कर दिया, जबकि प्रत्यक्षवाद ने केवल उन्हीं तथ्यों को स्वीकार किया जिन्हें अनुभवजन्य रुप से सत्यापित किया जा सके। इन प्रवृत्तियों के कारण राजनीतिक चिंतन के मानकीय पहलुओं की उपेक्षा हुई, जिससे सिद्धांत निर्माण की शास्त्रीय परंपरा कमजोर हो गई और मौलिक चिंतन का ह्रास हुआ।

14. (D) कथन I असत्य है, लेकिन कथन II सत्य है।
नकारात्मक स्वतंत्रता और परिणामों की समानता अक्सर परस्पर विरोधी लक्ष्य माने जाते हैं, क्योंकि समानता स्थापित करने के लिए राज्य को व्यक्तिगत हस्तक्षेप करना पड़ता है। नकारात्मक स्वतंत्रता किसी भी प्रकार के बाहरी हस्तक्षेप का विरोध करती है। इसके विपरीत, सकारात्मक स्वतंत्रता व्यक्ति के आत्म-विकास के लिए राज्य की सक्रिय भूमिका और आवश्यक सुविधाओं के प्रावधान पर बल देती है। राज्य का यही हस्तक्षेप नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थकों द्वारा एक खतरे के रूप में देखा जाता है। अतः कथन II पूर्णतः तर्कसंगत है।

15. (B) केवल I और III
मध्यकालीन राजनीतिक चिंतन में चर्च ने आत्माओं के कल्याण हेतु आध्यात्मिक अधिकार का दावा किया, जबकि राज्य को सांसारिक व्यवस्था बनाए रखने हेतु लौकिक अधिकार दिया गया। यद्यपि दो तलवारों के सिद्धांत ने इनके पृथक्करण का प्रयास किया, किंतु व्यवहार में इनके अधिकार क्षेत्र अक्सर एक-दूसरे में हस्तक्षेप करते रहे। सर्वोच्चता और अधिकार की सीमा को लेकर पोप और सम्राट के बीच निरंतर विवाद होते रहे। अतः यह संबंध काफी जटिल थे, जिसमें दोनों सत्ताएँ अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने का प्रयास करती रहती थीं।

16. (B) मूल्यों और प्रासंगिकता के महत्व पर ध्यान केंद्रित करना।
उत्तर-व्यवहारवाद का सबसे महत्वपूर्ण योगदान राजनीतिक शोध में मूल्यों की पुनरावृत्ति और सामाजिक प्रासंगिकता पर बल देना है। इसने व्यवहारवाद की उस प्रवृत्ति का विरोध किया जो केवल तकनीकी शुद्धता और तथ्य-आधारित विश्लेषण तक सीमित थी। उत्तर-व्यवहारवाद के अनुसार, राजनीतिक विज्ञान का उद्देश्य केवल आँकड़े एकत्र करना नहीं, बल्कि समाज के ज्वलंत मुद्दों का समाधान खोजना होना चाहिए। "प्रासंगिकता और कार्य" इसके दो मुख्य स्तंभ थे, जिन्होंने अनुशासन को मानवीय समस्याओं के प्रति अधिक संवेदनशील और उत्तरदायी बनाया।

17. (B) किसान बहुसंख्यक वाला एक बड़ा कृषि प्रधान समाज।
माओ जेदोंग का लंबी अवधि के जनयुद्ध का सिद्धांत विशेष रूप से उन देशों के लिए तैयार किया गया था जहाँ की अर्थव्यवस्था मुख्य रुप से कृषि पर आधारित थी। माओ ने मार्क्सवाद को चीनी परिस्थितियों के अनुरुप ढालते हुए किसानों को क्रांति की मुख्य शक्ति माना। यह रणनीति ग्रामीण इलाकों में आधार क्षेत्र स्थापित करने और वहां से शहरों को घेरने पर केंद्रित थी। औद्योगिक रूप से पिछड़े लेकिन विशाल ग्रामीण जनसंख्या वाले समाजों में परिवर्तन लाने के लिए यह सिद्धांत एक अत्यंत प्रभावशाली माध्यम साबित हुआ।

18. (A) संसाधनों के आवंटन के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाओं की निष्पक्षता।
प्रक्रियात्मक न्याय इस मूल विचार पर आधारित है कि यदि किसी परिणाम तक पहुंचने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी है, तो परिणाम भी न्यायपूर्ण माना जाएगा। यह संसाधनों के अंतिम वितरण के बजाय उन नियमों और विधियों की शुद्धता पर ध्यान केंद्रित करता है जो आवंटन के लिए उपयोग किए जाते हैं। इसमें कानून के समक्ष समानता और उचित प्रक्रिया का पालन अनिवार्य होता है। यह अवधारणा

NODIA

उदारवादी राजनीतिक व्यवस्थाओं में अधिकारों की सुरक्षा और न्याय की व्याख्या हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है।

19. (C) जटिल समाजों के शासन के लिए यह अक्सर बहुत धीमा होता है।
प्रत्यक्ष लोकतंत्र की एक प्रमुख आलोचना यह है कि आधुनिक बड़े और जटिल समाजों में सभी नागरिकों की सीधी भागीदारी अत्यंत कठिन और समय लेने वाली होती है। प्रत्येक नीतिगत निर्णय पर जनता की सहमति प्राप्त करना शासन की गति को धीमा कर देता है, जो संकटकालीन स्थितियों में घातक हो सकता है। इसके अलावा, तकनीकी विषयों पर व्यापक जनमत प्राप्त करना और प्रबंधकीय जटिलताओं को सुलझाना एक बड़ी चुनौती है। यही कारण है कि अधिकांश आधुनिक राष्ट्रों ने प्रत्यक्ष के स्थान पर प्रतिनिधि लोकतंत्र को अपनाया है।

20. (B) P-2, Q-4, R-1, S-3
सकारात्मक स्वतंत्रता का संबंध व्यक्ति के आत्म-साक्षात्कार और उसकी क्षमताओं को विकसित करने से है। सामाजिक न्याय समाज में संसाधनों और अवसरों के उचित तथा तर्कसंगत वितरण पर बल देता है। व्यवहारवाद राजनीति के अध्ययन में अनुभवजन्य विधियों और अवलोकनीय आँकड़ों के प्रयोग को प्राथमिकता देता है। दो तलवारों का सिद्धांत मध्यकालीन यूरोप में आध्यात्मिक और लौकिक सत्ताओं के बीच अधिकार के विभाजन की व्याख्या करता है। ये चारों अवधारणाएं राजनीति विज्ञान के विभिन्न आयामों और ऐतिहासिक विकास के चरणों को प्रभावी ढंग से स्पष्ट करती हैं।

21. (C) अहिंसा के माध्यम से नैतिक परिवर्तन।
गांधीवादी परिवर्तन का सिद्धांत पूर्णतः अहिंसा और सत्य के सिद्धांतों पर आधारित है। गांधीजी का मानना था कि वास्तविक सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन केवल बाहरी व्यवस्था बदलने से नहीं, बल्कि व्यक्ति के आंतरिक नैतिक उत्थान से ही संभव है। सत्याग्रह के माध्यम से विरोधी के हृदय को परिवर्तित करना उनका मुख्य उद्देश्य था। उनके अनुसार साध्य की प्राप्ति के लिए साधनों की शुद्धता अनिवार्य है। यह दृष्टिकोण दमनकारी सत्ताओं के विरुद्ध संघर्ष के लिए नैतिक शक्ति और आत्मिक बल को प्राथमिक उपकरण के रूप में स्वीकार करता है।

22. (B) राजनीतिक व्यवहार में खोजे जाने योग्य एकरूपताएँ मौजूद हैं।
व्यवहारवादी दृष्टिकोण के अनुसार, मानवीय राजनीतिक व्यवहार पूरी तरह यादृच्छिक नहीं होता, बल्कि उसमें कुछ निश्चित नियमितताएँ और एकरूपताएँ पाई जाती हैं। इन नियमितताओं का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन किया जा सकता है, जिससे सामान्यीकरण और सिद्धांतों का निर्माण संभव होता है। व्यवहारवादियों का मानना था कि यदि हम पर्याप्त आँकड़े और अनुभवजन्य साक्ष्य एकत्र करें, तो हम राजनीतिक प्रवृत्तियों की भविष्यवाणी कर सकते हैं। यह अवधारणा राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञानों की भांति अधिक व्यवस्थित और भविष्योन्मुखी अनुशासन बनाने के लक्ष्य की दिशा में केंद्रीय है।

23. (D) पोप जेलासियस।
दो तलवारों का सिद्धांत ऐतिहासिक रूप से पोप जेलासियस प्रथम द्वारा सम्राट अनास्तासियस को लिखे गए एक पत्र से उत्पन्न हुआ था। ईस्वी 494 के इस पत्र में पोप ने तर्क दिया कि संसार का शासन दो सत्ताओं द्वारा किया जाता है: पुरोहितों का पवित्र अधिकार और राजाओं की लौकिक शक्ति। जेलासियस ने स्पष्ट किया कि आध्यात्मिक मामलों में पुरोहित शासकों से श्रेष्ठ हैं। यह सिद्धांत कालांतर में चर्च और राज्य के मध्य सत्ता संघर्ष का मुख्य आधार बना और मध्यकालीन राजनीतिक दर्शन में अधिकार क्षेत्र के विभाजन का मानक रूपक बन गया।

24. (A) सारवान लोकतंत्र
एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जहाँ नियमित चुनाव तो होते हैं, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विपक्ष का दमन किया जाता है, उसे सारवान लोकतंत्र का अभाव माना जाता है। यहाँ चुनावी प्रक्रिया केवल एक औपचारिकता बनकर रह जाती है, जिसे प्रक्रियात्मक लोकतंत्र कहा जा सकता है। सारवान लोकतंत्र में केवल मतदान पर्याप्त नहीं है, बल्कि नागरिक अधिकारों की सुरक्षा, न्याय और वास्तविक जनभागीदारी का होना अनिवार्य है। ऐसी व्यवस्थाएँ लोकतांत्रिक तो दिखती हैं, परंतु उनके भीतर लोकतांत्रिक मूल्यों और उदारवादी सिद्धांतों का पूर्णतः अभाव होता है।

25. (A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
गांधीजी के लिए सत्याग्रह केवल एक राजनीतिक तकनीक नहीं थी, बल्कि यह सत्य की खोज पर आधारित जीवन जीने का एक व्यापक मार्ग था। इसमें अहिंसक शक्ति का उपयोग करके समाज और व्यवस्था में न्यायपूर्ण परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है। सत्याग्रह का मूल मंत्र है कि सत्य के प्रति अटूट निष्ठा और कष्ट सहने की क्षमता के माध्यम से अन्याय का विरोध किया जाए। यह दर्शन मानता है कि नैतिक बल किसी भी भौतिक शक्ति से श्रेष्ठ है, जो व्यक्ति और समाज दोनों को रूपांतरित करने में सक्षम है।

26. (A) वैज्ञानिकों को सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए ज्ञान का प्रयोग करना चाहिए।
उत्तर-व्यवहारवाद का "प्रासंगिकता और कार्य" का नारा इस विचार को व्यक्त करता है कि राजनीति विज्ञान का शोध केवल बौद्धिक अभ्यास तक सीमित नहीं होना चाहिए। वैज्ञानिकों की यह नैतिक जिम्मेदारी है कि वे अपने ज्ञान का उपयोग समाज की ज्वलंत समस्याओं और संकटों को सुलझाने के लिए करें। केवल आँकड़ों का संग्रह और तकनीकी शुद्धता पर्याप्त नहीं है, बल्कि शोध का उद्देश्य सामाजिक सुधार और सकारात्मक परिवर्तन होना चाहिए। यह दृष्टिकोण विद्वानों को अपनी शैक्षणिक सीमाओं से बाहर निकलकर सक्रिय रूप से मानवीय कल्याण में योगदान देने हेतु प्रेरित करता है।

27. (D) व्यक्तिगत न्याय
कानून के समक्ष समानता की अवधारणा व्यक्तिगत न्याय की आधारशिला है, जो यह सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के समान कानूनी सुरक्षा प्राप्त हो। यह सिद्धांत उदारवादी न्याय प्रणाली का केंद्र है, जहाँ कानून

Click Here to Buy book on Amazon

की नजर में सभी नागरिक समान होते हैं और किसी को भी विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होते। व्यक्तिगत न्याय मुख्य रूप से निष्पक्ष सुनवाई, उचित कानूनी प्रक्रिया और अधिकारों के संरक्षण पर बल देता है। यह व्यक्तियों के साथ उनके कार्यों और कानूनों के आधार पर समान व्यवहार सुनिश्चित करने की गारंटी प्रदान करता है।

28. (B) धर्मनिरपेक्ष शासकों पर पोप की सर्वोच्चता।
मध्यकालीन चर्च-राज्य विवादों में यह तर्क दिया गया कि आध्यात्मिक तलवार, जो आत्माओं की मुक्ति से संबंधित है, लौकिक तलवार से श्रेष्ठ है। इस तर्क का उपयोग धर्मनिरपेक्ष शासकों पर पोप की सर्वोच्चता को सिद्ध करने के लिए किया गया। चर्च के समर्थकों के अनुसार, चूँकि राजाओं को भी अपनी आत्मा के उद्धार के लिए चर्च पर निर्भर रहना पड़ता है, इसलिए उन्हें आध्यात्मिक सत्ता के अधीन होना चाहिए। इस विचारधारा ने मध्यकाल में पोप को राजाओं को नियुक्त करने या उन्हें पदच्युत करने का नैतिक और राजनीतिक अधिकार प्रदान करने का प्रयास किया था।

29. (C) साम्राज्यवाद
लेनिन ने अपनी प्रसिद्ध व्याख्या में साम्राज्यवाद को पूंजीवाद की सर्वोच्च और अंतिम अवस्था के रूप में वर्णित किया। उनके अनुसार, जब पूंजीवाद अपने घरेलू बाजारों में संतृप्त हो जाता है, तो वह नए बाजारों, कच्चे माल और सस्ते श्रम की तलाश में दूसरे राष्ट्रों का शोषण शुरू कर देता है। एकाधिकार और वित्तीय पूंजी का वर्चस्व साम्राज्यवाद को जन्म देता है, जिससे अंततः राष्ट्रों के बीच युद्ध और वैश्विक संघर्ष बढ़ते हैं। लेनिन का मानना था कि साम्राज्यवाद का उदय सर्वहारा क्रांति के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करता है।

30. (B) 2, 3, 1
राजनीति विज्ञान के विकास में सबसे पहले परंपरावाद का प्रभाव था, जिसने मानकीय मूल्यों और ऐतिहासिक संस्थानों के अध्ययन पर बल दिया। इसके पश्चात 1950 के दशक में व्यवहारवाद का उदय हुआ, जिसने अनुशासन को वैज्ञानिक बनाने और अवलोकनीय आँकड़ों पर ध्यान केंद्रित करने की वकालत की। व्यवहारवाद की कमियों के विरुद्ध 1960 के दशक के अंत में उत्तर-व्यवहारवाद अस्तित्व में आया, जिसने शोध में मूल्यों और सामाजिक प्रासंगिकता को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया। अतः यह क्रम अनुशासन के निरंतर बौद्धिक विकास और सुधार की प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से दर्शाता है।

31. (A) परिणाम की समानता
धनवानों पर उच्च कर लगाकर गरीबों के लिए सामाजिक कार्यक्रमों को वित्तपोषित करना परिणाम की समानता को बढ़ावा देने का एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। यह नीति केवल समान अवसर देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य समाज में मौजूद आर्थिक विषमताओं को सक्रिय रूप से कम करना है। राज्य द्वारा किया गया यह हस्तक्षेप संसाधनों का पुनर्वितरण सुनिश्चित करता है ताकि सभी नागरिकों के जीवन स्तर के बीच के अंतर को कम किया जा सके। यह समाजवादी और कल्याणकारी राज्य की अवधारणाओं के अनुरूप है जो आर्थिक न्याय की दिशा में कार्य करते हैं।

32. (B) महान दार्शनिक और मानकीय प्रश्न।
बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में राजनीतिक सिद्धांत का पुनरुत्थान मुख्य रूप से न्याय, स्वतंत्रता और व्यक्तिगत अधिकारों जैसे महान दार्शनिक और मानकीय प्रश्नों की ओर लौटने से हुआ। व्यवहारवाद के प्रभाव के कारण इन मूल्यों की उपेक्षा हुई थी, जिससे राजनीतिक चिंतन केवल आँकड़ा विश्लेषण तक सीमित रह गया था। पुनरुत्थान के दौर में विचारकों ने राजनीति के नैतिक और दार्शनिक आधारों को पुनः स्थापित किया। इस कालखंड में राजनीतिक सिद्धांत ने फिर से एक जीवंत रूप धारण किया, जो मानवीय अस्तित्व के मौलिक प्रश्नों पर गहन विचार करता है।

33. (C) अंतिम उपाय के रूप में रणनीतिक हिंसा
गांधीवादी सत्याग्रह में हिंसा के किसी भी रूप के लिए कोई स्थान नहीं है, चाहे वह रणनीतिक ही क्यों न हो। सत्याग्रह का अर्थ है सत्य के प्रति आग्रह, जो पूर्णतः अहिंसा और आत्म-पीड़ा के माध्यम से विरोधी का हृदय परिवर्तन करने पर आधारित है। सविनय अवज्ञा, असहयोग और उपवास इसके प्रमुख अंग हैं, जिनका उपयोग अन्यायपूर्ण कानूनों और नीतियों का विरोध करने के लिए किया जाता है। गांधीजी का मानना था कि हिंसा का प्रयोग कभी भी न्यायपूर्ण समाज की स्थापना नहीं कर सकता, क्योंकि साध्य की नैतिकता साधनों की शुद्धता पर निर्भर करती है।

34. (A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।
व्यवहारवाद ने तथ्यों और मूल्यों के बीच स्पष्ट विभाजन का समर्थन किया, यह तर्क देते हुए कि वैज्ञानिक शोध को केवल अनुभवजन्य तथ्यों तक सीमित रहना चाहिए। इसके विपरीत, उत्तर-व्यवहारवाद ने इस द्विभाजन को अपूर्ण माना और तर्क दिया कि राजनीतिक विश्लेषण में मूल्य और तथ्य एक-दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। उत्तर-व्यवहारवादियों का मानना था कि मूल्यों के बिना शोध उद्देश्यहीन हो जाता है और तथ्यों का चयन भी शोधकर्ता के मूल्यों से प्रभावित होता है। अतः दोनों कथन राजनीति विज्ञान के विकास में आए महत्वपूर्ण वैचारिक परिवर्तनों को सही ढंग से प्रस्तुत करते हैं।

35. (B) केवल I और III
विचारधारा राजनीतिक वास्तविकता को समझने और उसका विश्लेषण करने के लिए एक व्यवस्थित रूपरेखा प्रदान करती है। यह व्यक्तियों और समूहों को साझा लक्ष्यों की ओर प्रेरित कर सामूहिक राजनीतिक कार्रवाई के लिए लामबंद करने का महत्वपूर्ण कार्य करती है। हालाँकि, यह कहना गलत है कि सभी विचारधाराएँ क्रांतिकारी होती हैं; कुछ विचारधाराएँ, जैसे रूढ़िवाद, वर्तमान व्यवस्था को बनाए रखने और उसमें क्रमिक सुधार की पक्षधर होती हैं। अतः विचारधाराएँ समाज में स्थिरता और परिवर्तन दोनों की भूमिका निभा सकती हैं, जो उनके विशिष्ट लक्ष्यों और संदर्भों पर निर्भर करता है।

NODIA

36. (D) किसानों को प्राथमिक क्रांतिकारी शक्ति मानना।
शास्त्रीय मार्क्सवाद-लेनिनवाद मुख्य रूप से औद्योगिक सर्वहारा वर्ग को क्रांति का नेतृत्वकर्ता मानता है, लेकिन माओ जेदोंग ने इस विचार को चीन की ग्रामीण स्थितियों के अनुरूप बदला। माओ का सबसे मौलिक योगदान किसानों को मुख्य क्रांतिकारी शक्ति के रूप में पहचानना था। उन्होंने तर्क दिया कि एक कृषि प्रधान समाज में क्रांति का आधार ग्रामीण क्षेत्र होना चाहिए। यह दृष्टिकोण मार्क्सवादी सिद्धांतों का एक महत्वपूर्ण रूपांतरण था, जिसने तीसरी दुनिया के अन्य कृषि प्रधान राष्ट्रों में क्रांतिकारी आंदोलनों के लिए एक नया मॉडल और प्रेरणा प्रदान करने का कार्य किया।

37. (B) सांसारिक, धर्मनिरपेक्ष मामलों से संबंधित शक्ति।
मध्यकालीन यूरोप में 'लौकिक शक्ति' का तात्पर्य राजाओं और सम्राटों के उस अधिकार से था जो सांसारिक, भौतिक और धर्मनिरपेक्ष मामलों से संबंधित था। इसमें कानून व्यवस्था बनाए रखना, रक्षा करना और समाज का प्रशासन चलाना शामिल था। यह आध्यात्मिक शक्ति से भिन्न थी, जिसका केंद्र चर्च और मानव आत्मा का कल्याण था। दो तलवारों के सिद्धांत के अंतर्गत लौकिक शक्ति को एक पृथक अधिकार क्षेत्र माना गया था, हालाँकि इसकी सीमाएँ और आध्यात्मिक शक्ति के साथ इसके संबंध मध्ययुगीन राजनीतिक बहस के सबसे विवादास्पद और जटिल विषय बने रहे।

38. (C) राजनीतिक समानता
'एक व्यक्ति, एक वोट' का सिद्धांत राजनीतिक समानता की मौलिक अभिव्यक्ति है, जो यह सुनिश्चित करता है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में प्रत्येक नागरिक की आवाज का मूल्य समान हो। यह सिद्धांत जाति, धर्म, संपत्ति या लिंग के आधार पर मतदान के अधिकार में किसी भी भेदभाव को पूरी तरह अस्वीकार करता है। यह अवधारणा इस विश्वास पर आधारित है कि राजनीतिक संप्रभुता संपूर्ण जनता में निहित है और सरकार की वैधता सभी नागरिकों की समान भागीदारी से प्राप्त होती है। राजनीतिक समानता आधुनिक लोकतंत्र का अनिवार्य आधार है, जो नागरिक अधिकारों को सुरक्षित करती है।

39. (C) स्ट्रॉसियन दृष्टिकोण
लियो स्ट्रॉस और उनके समर्थकों ने राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद के उदय की कड़ी आलोचना की और इसे राजनीतिक सिद्धांत के पतन का मुख्य कारण माना। उनका तर्क था कि आधुनिक सामाजिक विज्ञान ने अपनी शास्त्रीय और मानकीय जड़ों को त्याग दिया है, जिससे न्याय और सद्गुण जैसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की उपेक्षा हुई है। स्ट्रॉसियन दृष्टिकोण महान दार्शनिक ग्रंथों के गहन अध्ययन और उन शाश्वत सत्यों की ओर लौटने की वकालत करता है जो राजनीतिक जीवन का मार्गदर्शन करते हैं। यह विचारधारा राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान में एक प्रमुख बौद्धिक शक्ति के रूप में उभरी।

40. (A) P-3, Q-1, R-2, S-4
महात्मा गांधी ने राज्य को एक ऐसी हिंसक संस्था माना जो व्यक्ति की स्वतंत्रता और स्वायत्तता को दबाती है। लेनिन ने मार्क्सवादी दृष्टिकोण अपनाते हुए राज्य को एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के शोषण और उत्पीड़न का उपकरण बताया। माओ जेदोंग ने क्रांति के पश्चात जनता की तानाशाही की वकालत की ताकि समाजवाद को सुरक्षित रखा जा सके। वहीं जॉन लॉक ने सामाजिक अनुबंध के माध्यम से राज्य की स्थापना का तर्क दिया, जिसका उद्देश्य व्यक्तियों के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करना और समाज में व्यवस्था बनाए रखना है।

41. (C) संसाधनों और अवसरों का उचित वितरण।
सामाजिक न्याय की अवधारणा का केंद्र समाज में संसाधनों, धन और अवसरों का उचित और तर्कसंगत वितरण सुनिश्चित करना है। यह केवल व्यक्तिगत कानूनों के पालन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज की बुनियादी संरचना में निष्पक्षता लाने का प्रयास करता है। सामाजिक न्याय का उद्देश्य उन सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को दूर करना है जो लोगों को अपनी पूर्ण क्षमता प्राप्त करने से रोकती हैं। यह वंचित वर्गों को सशक्त बनाने और एक समावेशी समाज के निर्माण पर बल देता है जहाँ प्रत्येक व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार हो।

42. (C) यह शुद्ध, अवैज्ञानिक परंपरावाद की ओर वापसी थी।
उत्तर-व्यवहारवाद को परंपरावाद की ओर वापसी के रूप में देखना गलत है। वास्तव में, यह व्यवहारवाद की वैज्ञानिक पद्धतियों को अस्वीकार नहीं करता था, बल्कि उन्हें अधिक प्रासंगिक और मूल्य-आधारित बनाने का प्रयास था। इसने तर्क दिया कि तकनीक को विषय-वस्तु से अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए और वैज्ञानिकों को सामाजिक समस्याओं के समाधान में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। उत्तर-व्यवहारवाद ने अनुभवजन्य शोध के साथ-साथ मानकीय दृष्टिकोण के एकीकरण का आह्वान किया ताकि राजनीति विज्ञान समाज के लिए वास्तव में उपयोगी और सार्थक शोध प्रस्तुत कर सके।

43. (C) जेलासियन सिद्धांत
मध्यकालीन राजनीतिक दर्शन में यह विचार कि ईश्वर ने दो तलवारें प्रदान की हैं, जेलासियस के सिद्धांत का एक सरलीकृत प्रतिनिधित्व है। पोप जेलासियस प्रथम ने यह तर्क दिया था कि धार्मिक मामलों में चर्च का अधिकार सर्वोच्च है, जबकि नागरिक मामलों में सम्राट का शासन होना चाहिए। यह द्वैतवाद मध्यकालीन यूरोप में चर्च और राज्य के बीच शक्तियों के संतुलन और उनके पृथक अधिकार क्षेत्रों को परिभाषित करने का एक महत्वपूर्ण आधार बना। हालाँकि, समय के साथ दोनों सत्ताओं ने एक-दूसरे के कार्यक्षेत्रों में हस्तक्षेप करके अपनी सर्वोच्चता सिद्ध करने का प्रयास किया।

44. (D) एक सरकार नागरिकों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षा प्रदान करती है।
सकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा व्यक्ति को उसकी क्षमताओं को विकसित करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम बनाने पर केंद्रित है। सरकार द्वारा मुफ्त या सुलभ शिक्षा प्रदान करना इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है, क्योंकि यह व्यक्ति को वह साधन प्रदान करता है जिससे वह स्वतंत्र रूप से कार्य करने और समाज में योगदान देने के योग्य बन सके। यह केवल बाधाओं के अभाव तक सीमित नहीं है, बल्कि उन परिस्थितियों

का निर्माण करना है जिनमें व्यक्ति अपनी वास्तविक क्षमता को साकार कर सके। यह दृष्टिकोण व्यक्ति के विकास हेतु राज्य की सक्रिय भूमिका को आवश्यक मानता है।

45. (A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
व्यवहारवादी क्रांति का मुख्य उद्देश्य राजनीति विज्ञान को एक विशुद्ध विज्ञान के रूप में स्थापित करना था। व्यवहारवादियों ने तर्क दिया कि शोध केवल उन अवलोकनीय आँकड़ों और व्यवहारों पर आधारित होना चाहिए जिनका वैज्ञानिक रूप से मापन और सत्यापन किया जा सके। उन्होंने राजनीति के अध्ययन में मानकीय मूल्यों और दार्शनिक अटकलों के स्थान पर अनुभवजन्य पद्धतियों और सांख्यिकीय विश्लेषण को प्राथमिकता दी। यह आंदोलन अनुशासन को पारंपरिक ऐतिहासिक और कानूनी वर्णनों से मुक्त कर एक व्यवस्थित और वस्तुनिष्ठ वैज्ञानिक आधार प्रदान करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम था।

46. (B) चीनी समाज से पूंजीवादी तत्वों को बाहर निकालना।
माओ जेदोंग द्वारा शुरु की गई सांस्कृतिक क्रांति का प्राथमिक उद्देश्य चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और समाज के भीतर से उन पूंजीवादी और पारंपरिक तत्वों को समाप्त करना था जो उनके अनुसार समाजवादी मूल्यों के लिए खतरा थे। माओ का मानना था कि क्रांति की भावना को जीवित रखने के लिए निरंतर संघर्ष आवश्यक है। इस आंदोलन के माध्यम से उन्होंने युवा पीढ़ी को लामबंद किया और पार्टी की संरचना को अपने कट्टरपंथी सिद्धांतों के अनुरूप पुनर्गठित करने का प्रयास किया। यह चीनी इतिहास का एक अत्यंत गहन और उथल-पुथल वाला कालखंड था।

47. (C) असहयोग - गांधी
महात्मा गांधी ने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध 'असहयोग' को एक प्रमुख अहिंसक हथियार के रूप में विकसित किया, जिसका उद्देश्य अन्यायपूर्ण व्यवस्था को नैतिक रूप से पंगु बनाना था। अन्य विकल्पों की बात करें तो, लेनिन का मुख्य योगदान 'अग्रगामी दल' की अवधारणा है, जबकि 'लंबी अवधि का जनयुद्ध' माओ जेदोंग का प्रमुख सिद्धांत है। 'दो तलवारों का सिद्धांत' मध्यकालीन ईसाई राजनीतिक दर्शन से संबंधित है, न कि कार्ल मार्क्स से। अतः गांधी और असहयोग का युग्म पूरी तरह सही है, जो उनके संघर्ष की विशिष्ट पद्धति को दर्शाता है।

48. (A) रॉल्स और नोज़िक जैसे विचारकों के महत्व का नवीनीकरण।
राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान की मुख्य विशेषता जॉन रॉल्स, रॉबर्ट नोज़िक और हन्ना आरेंड्ट जैसे महान विचारकों के कार्यों का उदय था। इन विद्वानों ने न्याय, अधिकार, स्वतंत्रता और सामुदायिक जीवन जैसे मानकीय प्रश्नों पर फिर से गहराई से विचार किया। विशेष रूप से रॉल्स की "न्याय का सिद्धांत" ने राजनीतिक दर्शन को एक नई दिशा दी और इसे बौद्धिक विमर्श के केंद्र में पुनः स्थापित किया। इस दौर ने यह सिद्ध किया कि व्यवहारवाद की वैज्ञानिक पद्धतियों के बावजूद, राजनीति के नैतिक आधारों पर चर्चा करना अनिवार्य और प्रासंगिक है।

49. (C) सामाजिक न्याय
सामाजिक न्याय की अवधारणा विशेष रूप से समाज के वंचित और पिछड़े वर्गों को समान अवसर प्रदान करने और उनकी स्थिति में सुधार लाने से संबंधित है। यह केवल औपचारिक नियमों के पालन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उन ऐतिहासिक और संरचनात्मक अन्यायों को दूर करने का प्रयास करता है जो समाज में गहरी असमानता पैदा करते हैं। सामाजिक न्याय के अंतर्गत ऐसी नीतियों का समर्थन किया जाता है जो संसाधनों और अवसरों का पुनर्वितरण करती हैं ताकि समाज के सभी सदस्यों को गरिमापूर्ण जीवन और विकास की समान संभावनाएँ प्राप्त हो सकें।

50. (B) अंतिम संप्रभुता
मध्यकालीन यूरोप में चर्च और राज्य के बीच संघर्ष का मूल विषय अंतिम संप्रभुता और सर्वोच्च अधिकार का निर्धारण करना था। विवाद इस बात पर केंद्रित था कि क्या सम्राट को पोप के अधीन होना चाहिए या क्या दोनों सत्ताओं के अधिकार क्षेत्र पूरी तरह स्वतंत्र और स्वायत्त हैं। चर्च ने आध्यात्मिक श्रेष्ठता के आधार पर राजाओं को नियुक्त करने और हटाने के अधिकार का दावा किया, जबकि राजाओं ने अपने शासन को दैवीय और स्वतंत्र सिद्ध करने का प्रयास किया। यह दीर्घकालिक संघर्ष अंततः आधुनिक राष्ट्र-राज्य और धर्मनिरपेक्षता की अवधारणाओं के विकास का मार्ग बना।

51. (A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।
लेनिन का मानना था कि श्रमिक वर्ग अपने दैनिक संघर्षों के माध्यम से केवल 'ट्रेड-यूनियन चेतना' यानी आर्थिक सुधारों की मांग तक ही सीमित रह सकता है। उनके अनुसार, एक क्रांतिकारी राजनीतिक चेतना केवल बाहर से और एक अनुशासित अग्रगामी दल के माध्यम से ही प्रदान की जा सकती है। उन्होंने तर्क दिया कि पेशेवर क्रांतिकारियों का यह दल श्रमिकों को संगठित करेगा और उन्हें पूंजीवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए नेतृत्व प्रदान करेगा। अतः ये दोनों कथन लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धांत और क्रांति की रणनीति के मूलभूत आधारों को स्पष्ट करते हैं।

52. (B) विचारों का एक सुसंगत समूह जो कार्रवाई के लिए कार्यक्रम प्रदान करता है।
राजनीति विज्ञान में विचारधारा को विचारों और विश्वासों के एक सुसंगत तंत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है जो न केवल राजनीतिक वास्तविकता की व्याख्या करता है, बल्कि उसे बदलने या बनाए रखने के लिए एक स्पष्ट कार्ययोजना भी प्रस्तुत करता है। विचारधाराएँ व्यक्तियों को राजनीतिक लक्ष्यों के इर्द-गिर्द संगठित करती हैं और उन्हें सामूहिक कार्रवाई के लिए प्रेरित करती हैं। यह मात्र व्यक्तिगत राय नहीं है, बल्कि एक व्यापक विश्वदृष्टि है जो सत्ता, न्याय और समाज के संगठन के बारे में मौलिक दिशा-निर्देश प्रदान करती है, जिससे शासन और विरोध को वैधता प्राप्त होती है।

53. (C) शोध में मूल्यों की भूमिका
व्यवहारवाद और उत्तर-व्यवहारवाद के बीच सबसे प्रमुख अंतर शोध में मूल्यों के स्थान को लेकर है। व्यवहारवाद ने

Downloaded from www.pdf.tube

'मूल्य-मुक्त' विश्लेषण की वकालत की, जहाँ तथ्यों को नैतिक निर्णयों से पूरी तरह अलग रखा जाता था। इसके विपरीत, उत्तर-व्यवहारवाद ने तर्क दिया कि राजनीति का अध्ययन मूल्यों से रहित नहीं हो सकता और शोध को मानवीय मूल्यों तथा सामाजिक प्रासंगिकता द्वारा निर्देशित होना चाहिए। उत्तर-व्यवहारवाद ने वैज्ञानिक पद्धतियों के साथ-साथ नैतिक जिम्मेदारी पर बल दिया, जिससे राजनीति विज्ञान को एक अधिक व्यापक दृष्टिकोण प्राप्त हुआ जो समाज की वास्तविक समस्याओं के प्रति संवेदनशील था।

54. (D) लोग उनके लिए निर्णय लेने हेतु अधिकारियों का चुनाव करते हैं।
प्रतिनिधि लोकतंत्र आधुनिक राष्ट्र-राज्यों में शासन का सबसे प्रचलित रूप है, जहाँ नागरिक सीधे कानून बनाने के बजाय अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। ये निर्वाचित अधिकारी जनता की ओर से निर्णय लेने और नीतियां बनाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। इस प्रणाली का मूल आधार यह है कि जनप्रतिनिधि अपनी जनता की इच्छाओं और हितों का प्रतिनिधित्व करेंगे और चुनावों के माध्यम से उनके प्रति जवाबदेह रहेंगे। यह व्यवस्था बड़े भौगोलिक क्षेत्रों और विशाल जनसंख्या वाले देशों में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को व्यावहारिक और प्रभावी बनाने के लिए अत्यंत उपयुक्त मानी जाती है।

55. (B) केवल I और III
महात्मा गांधी के परिवर्तन के सिद्धांत में साधनों की शुद्धता को साध्य से अधिक महत्व दिया गया है। उनका मानना था कि अनैतिक साधनों से कभी भी नैतिक साध्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त, उन्होंने व्यक्तिगत नैतिक जिम्मेदारी और आत्म-परिवर्तन पर अत्यधिक बल दिया, क्योंकि उनके अनुसार समाज का सुधार व्यक्ति के स्वयं के सुधार से शुरू होता है। गांधीजी ने राज्य को एक दमनकारी संस्था माना और इसलिए उन्होंने राज्य पर निर्भरता के बजाय विकेंद्रीकृत ग्राम स्वराज और स्वैच्छिक सहयोग को सामाजिक समस्याओं के समाधान के रूप में देखा।

56. (B) डेविड ईस्टन
1953 में अपनी पुस्तक "द पॉलिटिकल सिस्टम" में डेविड ईस्टन ने राजनीतिक सिद्धांत के पतन की प्रसिद्ध घोषणा की थी। उन्होंने तर्क दिया कि समकालीन राजनीतिक सिद्धांत केवल इतिहास लेखन तक सीमित रह गया है और इसमें रचनात्मकता तथा वैज्ञानिक स्पष्टता का अभाव है। ईस्टन के अनुसार, सिद्धांतकार नए सिद्धांतों का निर्माण करने के बजाय अतीत के विचारकों की व्याख्याओं में ही उलझे हुए थे। उनकी इस तीखी आलोचना ने व्यवहारवादी क्रांति को गति दी, जिसने राजनीति विज्ञान को आँकड़ा-आधारित और अनुभवजन्य शोध की दिशा में मोड़ने का प्रयास किया।

57. (D) ग्रामीण इलाकों में आधार क्षेत्र स्थापित करके।
माओ जेदोंग के अनुसार, एक अर्ध-औपनिवेशिक और कृषि प्रधान देश में क्रांति का मार्ग ग्रामीण क्षेत्रों से होकर गुजरता है। उनकी रणनीति "गांवों द्वारा शहरों को घेरने" की थी, जिसके लिए उन्होंने दुर्गम ग्रामीण इलाकों में क्रांतिकारी आधार क्षेत्र स्थापित करने पर बल दिया। इन क्षेत्रों में कम्युनिस्ट पार्टी अपनी सेना का निर्माण करती थी और जनता को संगठित कर धीरे-धीरे अपनी शक्ति का विस्तार करती थी। यह रणनीति साम्राज्यवादी शक्तियों और उनके स्थानीय सहयोगियों की कमजोर कड़ियों पर प्रहार करने और लंबी अवधि तक सशस्त्र संघर्ष जारी रखने के लिए अत्यंत प्रभावी सिद्ध हुई।

58. (A) पोप और सम्राट के बीच पदनियुक्ति विवाद।
पदनियुक्ति विवाद मध्यकालीन यूरोप में दो तलवारों के सिद्धांत में निहित गहरे तनाव का सबसे प्रमुख उदाहरण है। यह विवाद इस प्रश्न पर था कि बिशपों और अन्य चर्च अधिकारियों को नियुक्त करने का अधिकार किसके पास है—पोप के पास या सम्राट के पास। यह मात्र एक प्रशासनिक मुद्दा नहीं था, बल्कि इसमें चर्च की विशाल भूमि और संपत्ति पर नियंत्रण की राजनीतिक शक्ति भी निहित थी। सम्राट चाहते थे कि चर्च पदानुक्रम उनके प्रति वफादार रहे, जबकि चर्च ने इस अधिकार को पूर्णतः आध्यात्मिक मानते हुए अपने पास रखने का दावा किया। इससे सत्ता के आध्यात्मिक और लौकिक स्रोतों के बीच गहरे अंतर्विरोध उजागर हुए।

59. (C) ऐतिहासिक नुकसान के लिए सामाजिक न्याय
सकारात्मक कार्रवाई की नीतियां सामाजिक न्याय की अवधारणा से गहराई से जुड़ी हुई हैं, जिनका उद्देश्य ऐतिहासिक रूप से उत्पीड़ित और वंचित समूहों के नुकसान की भरपाई करना है। ये नीतियां यह मानती हैं कि केवल औपचारिक समानता पर्याप्त नहीं है क्योंकि कुछ समूहों को सदियों से अवसरों से वंचित रखा गया है। अतः उन्हें शिक्षा और रोजगार में विशेष रियायतें या आरक्षण प्रदान करके समाज की मुख्यधारा में लाना अनिवार्य है। यह वितरणात्मक न्याय का एक रूप है जो समाज के विभिन्न वर्गों के बीच वास्तविक समानता स्थापित करने और सामाजिक असंतुलन को दूर करने का प्रयास करता है।

60. (C) P-4, Q-3, R-2, S-1
व्यवहारवाद का मुख्य आधार वैज्ञानिक 'सत्यापन' है, जो अवलोकनीय आँकड़ों के माध्यम से सिद्धांतों की पुष्टि करता है। उत्तर-व्यवहारवाद ने 'प्रासंगिकता' पर बल देते हुए राजनीतिक शोध को सामाजिक समस्याओं से जोड़ने का प्रयास किया। नकारात्मक स्वतंत्रता की पहचान 'बाधा के अभाव' के रूप में की जाती है, जहाँ व्यक्ति के कार्यों में कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होता। सकारात्मक स्वतंत्रता का लक्ष्य 'आत्म-प्रभुत्व' है, जिसमें व्यक्ति अपनी आंतरिक क्षमताओं और विवेक के माध्यम से स्वयं पर शासन करने और अपना पूर्ण विकास करने में सक्षम होता है। ये शब्द इन वैचारिक प्रवृत्तियों के मूल तत्व हैं।

61. (B) आम चुनाव में वोट डालना।
आम चुनाव में वोट डालना राजनीतिक समानता के सिद्धांत का सबसे प्रत्यक्ष और महत्वपूर्ण अनुप्रयोग है। यह इस विश्वास पर आधारित है कि लोकतंत्र में प्रत्येक वयस्क नागरिक को शासन की प्रक्रिया में भाग लेने का समान अधिकार है और प्रत्येक वोट का मूल्य बराबर है। राजनीतिक समानता किसी भी व्यक्ति की सामाजिक स्थिति, धन या शिक्षा की परवाह किए बिना

NODIA

उसे राजनीतिक निर्णय लेने की शक्ति में भागीदार बनाती है। यह नागरिक संप्रभुता को सुनिश्चित करने और सरकार की लोकतांत्रिक वैधता को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है, जो आधुनिक नागरिकता का आधार है।

62. (C) शोध प्राथमिकताओं को सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए।
उत्तर-व्यवहारवादी "प्रासंगिकता के सिद्धांत" का अर्थ था कि राजनीति विज्ञान के शोध को समाज की वास्तविक और ज्वलंत आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। विद्वानों ने तर्क दिया कि केवल अकादमिक उद्देश्यों के लिए आँकड़े एकत्र करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि शोध का उद्देश्य युद्ध, गरीबी और नस्लीय भेदभाव जैसी मानवीय समस्याओं का समाधान खोजना होना चाहिए। ज्ञान को कार्रवाई के साथ जोड़ा जाना चाहिए ताकि समाज में सार्थक सुधार लाए जा सकें। यह दृष्टिकोण अनुशासन को तकनीकी परिष्कार से ऊपर उठाकर सामाजिक प्रतिबद्धता और नैतिक जिम्मेदारी की दिशा में प्रेरित करता है।

63. (C) लेनिन
सर्वहारा की तानाशाही की अवधारणा लेनिन के परिवर्तन के सिद्धांत का केंद्र है। मार्क्सवादी विचारधारा का अनुसरण करते हुए लेनिन ने तर्क दिया कि पूंजीवाद को उखाड़ फेंकने के बाद एक संक्रमणकालीन अवस्था की आवश्यकता है, जहाँ श्रमिक वर्ग राज्य सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण रखेगा। इस अवस्था का उद्देश्य बुर्जुआ वर्ग के अवशेषों को समाप्त करना, प्रति-क्रांति को रोकना और समाजवाद की नींव रखना है। लेनिन के अनुसार, यह तानाशाही वास्तव में बहुसंख्यक जनता के लिए लोकतंत्र है और शोषक अल्पसंख्यक के विरुद्ध एक आवश्यक दमनकारी शक्ति है जो अंततः वर्गविहीन समाज का मार्ग प्रशस्त करती है।

64. (B) व्यक्तिगत न्याय लेनदेन संबंधी है; सामाजिक न्याय संरचनात्मक है।
व्यक्तिगत न्याय मुख्य रूप से व्यक्तियों के बीच होने वाले विशिष्ट लेनदेन, अनुबंधों और कानूनी अधिकारों की निष्पक्षता से संबंधित है। यह कानून की नजर में व्यक्ति के साथ होने वाले व्यवहार पर केंद्रित रहता है। इसके विपरीत, सामाजिक न्याय समाज की बुनियादी संरचना, संस्थानों और संसाधनों के वितरण के समग्र प्रतिमानों को संबोधित करता है। सामाजिक न्याय का उद्देश्य उन व्यापक सामाजिक और आर्थिक विषमताओं को दूर करना है जो व्यवस्था के भीतर गहराई से समाहित होती हैं। जहाँ व्यक्तिगत न्याय प्रक्रियात्मक शुद्धता चाहता है, वहीं सामाजिक न्याय समाज के वंचित वर्गों के लिए संरचनात्मक निष्पक्षता की मांग करता है।

65. (A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
मध्यकालीन यूरोप की राजनीतिक व्यवस्था वास्तव में अत्यंत विकेंद्रीकृत और जटिल थी, जिसे अक्सर 'अधिकारों के जाल' के रूप में वर्णित किया जाता है। एक तरफ पोप और सम्राट सार्वभौमिक संप्रभुता का दावा करते थे, तो दूसरी तरफ सामंती लॉर्ड्स अपने स्थानीय क्षेत्रों में वास्तविक शक्ति का प्रयोग करते थे। नागरिकों के पास चर्च, सम्राट और स्थानीय जागीरदार के प्रति अलग-अलग और कभी-कभी विरोधाभासी वफादारियाँ होती थीं। इस खंडित संरचना के कारण अधिकार क्षेत्रों में स्पष्टता का अभाव था, जिससे मध्यकाल में राजनीतिक और कानूनी विवादों का निरंतर जन्म होता रहा।

66. (B) नकारात्मक स्वतंत्रता
नकारात्मक स्वतंत्रता वह अवधारणा है जो व्यक्ति के लिए एक ऐसे हस्तक्षेप-मुक्त क्षेत्र की मांग करती है जहाँ वह अपनी इच्छानुसार कार्य कर सके। इसमें स्वतंत्रता का अर्थ केवल बाहरी बाधाओं या दूसरों द्वारा की जाने वाली जबरदस्ती की अनुपस्थिति है। इस दृष्टिकोण के अनुसार, राज्य का कार्य केवल व्यक्ति की इस निजी स्वतंत्रता की रक्षा करना है और उसे व्यक्ति के जीवन में तब तक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जब तक कि वह दूसरों को नुकसान न पहुँचाए। यह विचारधारा शास्त्रीय उदारवाद का आधार है, जो व्यक्तिगत स्वायत्तता और न्यूनतम राज्य की वकालत करती है।

67. (C) लोकतंत्र केवल मतदान के कार्य से संबंधित है।
लोकतंत्र की यह समझ कि यह केवल मतदान तक सीमित है, अत्यंत संकीर्ण और गलत है। यद्यपि चुनाव एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, परंतु वास्तविक लोकतंत्र में नागरिक अधिकारों की सुरक्षा, कानून का शासन, स्वतंत्र प्रेस, न्यायपालिका की स्वायत्तता और सामाजिक-आर्थिक न्याय जैसे सारवान तत्व भी अनिवार्य हैं। मतदान के बिना लोकतंत्र संभव नहीं है, लेकिन केवल मतदान एक व्यवस्था को लोकतांत्रिक नहीं बनाता यदि उसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों के संरक्षण जैसे मूल्यों का अभाव हो। अतः लोकतंत्र एक व्यापक जीवन पद्धति और शासन प्रणाली है।

68. (A) प्राकृतिक विज्ञान और निष्पक्षता की इच्छा।
राजनीति विज्ञान में व्यवहारवादी दृष्टिकोण पर प्राकृतिक विज्ञानों की पद्धतियों और निष्पक्षता की गहरी इच्छा का प्रभाव था। व्यवहारवादियों ने भौतिकी और जीव विज्ञान जैसे विषयों की भांति राजनीति का अध्ययन करने का प्रयास किया, जहाँ आँकड़ों को वस्तुनिष्ठ रूप से एकत्र और विश्लेषित किया जा सके। उन्होंने मानकीय दर्शन और ऐतिहासिक वृत्तांतों के स्थान पर सांख्यिकीय मॉडल, सर्वेक्षण और प्रयोगों को प्राथमिकता दी। इस आंदोलन का मुख्य लक्ष्य राजनीति विज्ञान को एक 'शुद्ध विज्ञान' के रूप में विकसित करना था, जो मानवीय व्यवहार में भविष्यवाणी करने योग्य नियमों और पैटर्न की खोज कर सके।

69. (B) राष्ट्र और साम्राज्यवाद।
माओ जेदोंग ने तर्क दिया कि पूर्व-क्रांतिकारी चीन जैसे देशों में, जो अर्ध-औपनिवेशिक थे, सबसे महत्वपूर्ण या "मुख्य अंतर्विरोध" चीनी राष्ट्र और विदेशी साम्राज्यवाद के बीच था। उनका मानना था कि जब तक विदेशी शक्तियों का प्रभुत्व बना रहेगा, तब तक आंतरिक वर्ग संघर्ष को पूरी तरह हल नहीं किया जा सकता। इसलिए, उन्होंने एक व्यापक 'संयुक्त मोर्चे' की वकालत की जिसमें साम्राज्यवादी विरोधी सभी देशभक्त वर्ग शामिल थे। इस दृष्टिकोण ने राष्ट्रवाद को क्रांति के साथ जोड़

Click Here to Buy book on Amazon

STUDYING FROM PDFs?

THINK AGAIN.

If you are studying only from PDFs,
you are wasting valuable time.

Research shows that learning from

PRINTED BOOKS has up to

4× HIGHER RETENTION

than studying from screens.

PRINT BOOK = BETTER MEMORY

PDF = LOWER RETENTION

Those who study from **PRINTED BOOKS**
move **AHEAD.**

Others are left **BEHIND**
in competition.

In competitive exams,
being average is not enough.

STAY ONE STEP AHEAD.

दिया, जिससे जापानी आक्रमण और अन्य विदेशी हस्तक्षेपों के विरुद्ध चीनी जनता को एकजुट करना संभव हो सका।

70. (D) कथन I असत्य है, लेकिन कथन II सत्य है।
दो तलवारों के सिद्धांत ने चर्च और राज्य के बीच के संघर्ष को हल करने के बजाय उसे और अधिक जटिल बना दिया। यद्यपि इसका उद्देश्य अधिकार क्षेत्रों को स्पष्ट करना था, परंतु पापल समर्थकों ने 'आध्यात्मिक श्रेष्ठता' का तर्क देकर लौकिक सत्ता पर नियंत्रण चाहा, जबकि शाही समर्थकों ने अपनी सत्ता को सीधे ईश्वर से प्राप्त बताकर चर्च के हस्तक्षेप का विरोध किया। इस वैचारिक द्वंद्व ने यूरोप में सदियों तक चलने वाले राजनीतिक तनाव और सत्ता संघर्ष को ईंधन दिया। अतः कथन II पूरी तरह सत्य है क्योंकि इस सिद्धांत की व्याख्या दोनों पक्षों ने अपने हितों के अनुसार की।

71. (A) सभी का कल्याण।
गांधीवादी अवधारणा 'सर्वोदय' का शाब्दिक अर्थ है "सभी का उदय" या "सभी का कल्याण"। यह विचार रस्किन की पुस्तक "अनटू दिस लास्ट" से प्रेरित है, जो समाज के अंतिम और सबसे कमजोर व्यक्ति के उत्थान पर बल देता है। पश्चिमी 'उपयोगितावाद', जो केवल "अधिकतम संख्या के अधिकतम सुख" की बात करता है, के विपरीत सर्वोदय बिना किसी भेदभाव के समाज के प्रत्येक सदस्य की प्रगति की कामना करता है। यह एक ऐसी सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था का स्वप्न है जो अहिंसा, सहयोग और न्याय पर आधारित हो, जहाँ कोई किसी का शोषण न करे।

72. (B) न्याय और अधिकारों के मानकीय प्रश्न।
बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान ने न्याय, स्वतंत्रता और व्यक्तिगत अधिकारों जैसे मानकीय और दार्शनिक प्रश्नों को बौद्धिक चर्चा के केंद्र में पुनः स्थापित किया। व्यवहारवाद के दौर में इन विषयों को 'अवैज्ञानिक' मानकर उपेक्षित कर दिया गया था। पुनरुत्थान के दौरान विचारकों ने यह तर्क दिया कि राजनीतिक जीवन को समझने के लिए केवल आँकड़े पर्याप्त नहीं है, बल्कि 'क्या होना चाहिए' और 'एक न्यायपूर्ण समाज क्या है' जैसे प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। इस प्रवृत्ति ने राजनीतिक चिंतन को फिर से एक समृद्ध और नैतिक रूप से जागरूक अनुशासन बना दिया।

73. (C) सामाजिक न्याय
सार्वभौमिक बुनियादी आय प्रदान करना सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है, क्योंकि यह समाज के प्रत्येक नागरिक को न्यूनतम आर्थिक सुरक्षा की गारंटी देता है। यह नीति इस विचार पर आधारित है कि संसाधनों का वितरण इस प्रकार होना चाहिए कि समाज में कोई भी व्यक्ति अत्यंत गरीबी या अभाव में न रहे। यह केवल औपचारिक समानता नहीं है, बल्कि यह व्यक्तियों को एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए आवश्यक साधन प्रदान करता है। सामाजिक न्याय के अंतर्गत ऐसी पुनर्वितरणकारी नीतियां समाज की बुनियादी संरचना को अधिक न्यायपूर्ण और मानवीय बनाने का कार्य करती हैं।

74. (D) राजनीतिक व्यवहार में खोजने योग्य एकरूपताएँ मौजूद हैं।
व्यवहारवाद का एक मूल विश्वास यह है कि मानवीय राजनीतिक व्यवहार में निश्चित एकरूपताएँ या नियमितताएँ मौजूद होती हैं जिनका व्यवस्थित अध्ययन संभव है। इन पैटर्न की पहचान करके राजनीतिक वैज्ञानिक सिद्धांतों का निर्माण कर सकते हैं और भविष्य की घटनाओं के बारे में विश्वसनीय भविष्यवाणियाँ कर सकते हैं। यह दृष्टिकोण मानकीय दर्शन के स्थान पर अनुभवजन्य प्रमाणों और आँकड़ों पर जोर देता है। व्यवहारवादियों का मानना था कि यदि राजनीति विज्ञान को एक सच्चा विज्ञान बनना है, तो उसे इन नियमितताओं को खोजने और सत्यापित करने के लिए वैज्ञानिक पद्धतियों का पूरी निष्ठा से पालन करना होगा।

75. (B) केवल II और III
उत्तर-व्यवहारवाद व्यवहारवाद का पूर्ण परित्याग नहीं था, बल्कि उसे सुधारने और अधिक प्रासंगिक बनाने का एक प्रयास था। इसे व्यवहारवाद की एक 'क्रांति' के रूप में देखा गया, न कि प्रति-क्रांति के रूप में। उत्तर-व्यवहारवादियों ने तर्क दिया कि राजनीति का अध्ययन मूल्यों से स्वतंत्र नहीं हो सकता और विद्वानों को समाज की वास्तविक समस्याओं के प्रति तटस्थ रहने के बजाय उनके समाधान के लिए सक्रिय रूप से प्रयास करना चाहिए। उन्होंने वैज्ञानिक पद्धतियों की उपयोगिता को स्वीकार किया, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि शोध का उद्देश्य सामाजिक सुधार और मानवीय कल्याण होना चाहिए।

76. (B) यशायाह बर्लिन
यशायाह बर्लिन अपने प्रसिद्ध निबंध "स्वतंत्रता की दो अवधारणाएं" के माध्यम से नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता के बीच अंतर को स्पष्ट करने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने नकारात्मक स्वतंत्रता को बाहरी बाधाओं की अनुपस्थिति और हस्तक्षेप-मुक्त क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया। वहीं सकारात्मक स्वतंत्रता को व्यक्ति के स्वयं का स्वामी होने और अपनी क्षमताओं को साकार करने की शक्ति के रूप में देखा गया। बर्लिन ने आगाह किया कि सकारात्मक स्वतंत्रता की गलत व्याख्या राज्य के तानाशाही पूर्ण नियंत्रण को सही ठहराने के लिए की जा सकती है। उनका यह वर्गीकरण आधुनिक राजनीतिक दर्शन में अत्यंत प्रभावशाली रहा है।

77. (C) क्रांति की मुख्य शक्ति के रूप में किसान वर्ग।
माओ जेदोंग की "गांवों द्वारा शहरों को घेरने" की प्रसिद्ध रणनीति उनके इस अडिग विश्वास का परिणाम थी कि चीन जैसे कृषि प्रधान समाज में किसान वर्ग ही क्रांति का मुख्य इंजन है। चूँकि शहरों में औद्योगिक मजदूर कम थे और वहां दमनकारी सत्ता की पकड़ मजबूत थी, इसलिए माओ ने दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रों को क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र बनाया। यहाँ उन्होंने जनसमर्थन हासिल किया और अपनी सैन्य शक्ति का निर्माण किया। यह रणनीति धीरे-धीरे शहरों की रसद काटकर और उन्हें अलग-थलग करके अंततः संपूर्ण राष्ट्र पर नियंत्रण प्राप्त करने की दिशा में अत्यंत सफल रही।

NODIA

78. (A) बिशपों और चर्च के अधिकारियों को नियुक्त करने का अधिकार।
मध्यकालीन यूरोप में चर्च और राज्य के बीच प्राथमिक संघर्ष पदनियुक्ति विवाद के रूप में उभरा, जो बिशपों और अन्य पादरियों की नियुक्ति के अधिकार से संबंधित था। यह केवल एक धार्मिक प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि इसमें चर्च की विशाल भूमि और संपत्ति पर नियंत्रण की राजनीतिक शक्ति भी निहित थी। सम्राट चाहते थे कि चर्च पदानुक्रम उनके प्रति वफादार रहें, जबकि पोप ने इस अधिकार को पूर्णतः आध्यात्मिक मानते हुए अपने पास रखने का दावा किया। इस संघर्ष ने सत्ता के आध्यात्मिक और लौकिक स्रोतों के बीच के गहरे अंतर्विरोधों को समाज के सामने उजागर किया।

79. (C) राज्य को संपत्ति की असमानताओं को कम करने के लिए कार्य करना चाहिए।
परिणाम की समानता की अवधारणा इस विचार पर आधारित है कि समाज के सभी व्यक्तियों के पास संसाधनों और जीवन स्तर का एक समान स्तर होना चाहिए। यह केवल समान अवसर देने से संतुष्ट नहीं है, बल्कि यह राज्य से सक्रिय हस्तक्षेप की मांग करती है ताकि संपत्ति और आय की गहरी खाइयों को पाटा जा सके। इसके समर्थकों का मानना है कि सामाजिक न्याय तभी संभव है जब लोगों के बीच के आर्थिक और भौतिक अंतर को न्यूनतम किया जाए। यह समाजवादी विचारधारा का एक प्रमुख लक्ष्य है, जो व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के स्थान पर सामूहिक कल्याण को प्राथमिकता देता है।

80. (B) 2, 3, 1
ऐतिहासिक दृष्टि से, लेनिन के नेतृत्व में रूस में बोल्शेविक क्रांति 1917 में हुई थी, जो आधुनिक विश्व की पहली सफल समाजवादी क्रांति थी। इसके पश्चात, महात्मा गांधी ने 1930 में भारत में प्रसिद्ध दांडी यात्रा और नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया, जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। अंत में, माओ जेदोंग ने 1966 में चीन में सांस्कृतिक क्रांति की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य समाज को कट्टरपंथी समाजवादी सिद्धांतों के अनुरूप बदलना था। यह क्रम बीसवीं शताब्दी के तीन महान राजनीतिक आंदोलनों और उनके विशिष्ट समयकाल को प्रभावी रूप से दर्शाता है।

81. (D) प्रासंगिकता
डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद के आठ प्रमुख "बौद्धिक आधारशिलाओं" का उल्लेख किया था, जिनमें नियमितता, सत्यापन, तकनीक, परिमाणीकरण, मूल्य-तटस्थता, व्यवस्थापन, शुद्ध विज्ञान और एकीकरण शामिल थे। 'प्रासंगिकता' इन आधारशिलाओं का हिस्सा नहीं थी; बल्कि यह उत्तर-व्यवहारवाद की मुख्य मांग के रूप में उभरी। व्यवहारवाद का ध्यान वैज्ञानिक पद्धतियों और आँकड़ों पर अधिक था, जबकि उत्तर-व्यवहारवाद ने बाद में यह तर्क दिया कि शोध की वैज्ञानिकता के साथ-साथ उसकी सामाजिक प्रासंगिकता भी अनिवार्य है। अतः प्रासंगिकता व्यवहारवादी आंदोलन के बजाय उसके परवर्ती सुधारवादी आंदोलन की विशेषता है।

82. (A) विचारधाराएँ मुद्दों को समझने का एक सरल तरीका प्रदान करती हैं।
विचारधारा को एक "नक्शा" कहना यह दर्शाता है कि यह जटिल राजनीतिक और सामाजिक दुनिया को समझने के लिए एक सरल और सुसंगत रूपरेखा प्रदान करती है। जैसे एक नक्शा हमें रास्ता दिखाने के लिए अनावश्यक विवरणों को हटाकर मुख्य दिशाओं पर ध्यान केंद्रित करता है, वैसे ही विचारधारा हमें यह बताती है कि क्या महत्वपूर्ण है और हमें किन लक्ष्यों की ओर बढ़ना चाहिए। यह अनगिनत तथ्यों और घटनाओं को एक अर्थ प्रदान करती है, जिससे आम नागरिक राजनीतिक प्रक्रियाओं को समझ सकें और उनमें अपनी भूमिका को पहचान सकें।

83. (C) व्यक्तियों का नैतिक उत्थान।
लेनिन के विपरीत, जिन्होंने राज्य सत्ता पर कब्जे और एक अनुशासित पार्टी के नेतृत्व को प्राथमिकता दी, गांधी के परिवर्तन के सिद्धांत का केंद्र व्यक्ति का नैतिक उत्थान और आत्म-सुधार था। गांधीजी का मानना था कि जब तक व्यक्ति स्वयं को सत्य और अहिंसा के मार्ग पर नहीं ले जाता, तब तक बाहरी राजनीतिक व्यवस्था में किया गया कोई भी बदलाव स्थाई या वास्तविक नहीं होगा। उनके लिए स्वराज का अर्थ केवल विदेशी शासन से मुक्ति नहीं, बल्कि अपनी इंद्रियों और स्वयं पर शासन करना था। यह दृष्टिकोण राजनीतिक संघर्ष को एक नैतिक साधना के रूप में देखता है।

84. (B) औपचारिक संस्थान व्यवहार में लोकतांत्रिक क्यों नहीं हो सकते हैं।
प्रक्रियात्मक और सारवान लोकतंत्र के बीच का अंतर यह समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि क्यों केवल चुनावों का होना एक देश को वास्तविक लोकतंत्र नहीं बनाता। प्रक्रियात्मक लोकतंत्र केवल मतदान और बहुदलीय व्यवस्था जैसे औपचारिक नियमों पर ध्यान देता है, जबकि सारवान लोकतंत्र यह देखता है कि क्या ये प्रक्रियाएं वास्तव में समानता, न्याय और जनता के अधिकारों की सुरक्षा कर रही हैं। यह अंतर हमें उन व्यवस्थाओं का विश्लेषण करने में मदद करता है जहाँ लोकतांत्रिक संस्थाएं तो मौजूद हैं, लेकिन व्यवहार में वे अधिनायकवादी या असमानतापूर्ण तरीके से कार्य करती हैं।

85. (A) P-4, Q-1, R-3, S-2
डेविड ईस्टन ने अपने प्रारंभिक कार्य में व्यवहारवाद के माध्यम से राजनीतिक सिद्धांत के पतन की चर्चा की और बाद में उन्होंने ही उत्तर-व्यवहारवाद के अंतर्गत 'प्रासंगिकता के सिद्धांत' की वकालत की। महात्मा गांधी ने अन्याय के विरुद्ध अहिंसक संघर्ष के लिए सत्याग्रह की अवधारणा प्रस्तुत की, जो उनके दर्शन का आधार है। लेनिन ने मार्क्सवादी क्रांति को सफल बनाने के लिए एक संगठित और अनुशासित 'अग्रगामी दल' की भूमिका को अनिवार्य माना। ये चारों अवधारणाएं राजनीति विज्ञान के ऐतिहासिक विकास और क्रांतिकारी विचारों के विभिन्न चरणों को पूरी तरह स्पष्ट करती हैं।

Downloaded from www.pdf.tube

86. (A) इसने आध्यात्मिक और लौकिक के बीच अधिकार के विभाजन को प्रतिपादित किया।
दो तलवारों के सिद्धांत का मूल मंत्र मानव जीवन के दो अलग-अलग आयामों—आध्यात्मिक और लौकिक—के लिए पृथक सत्ताओं के अस्तित्व को स्वीकार करना था। इस सिद्धांत के अनुसार, ईश्वर ने मानव जाति के कल्याण हेतु दो स्वतंत्र तलवारें (शक्तियाँ) दी हैं: एक चर्च के पास आत्माओं के मार्गदर्शन के लिए और दूसरी राज्य के पास व्यवस्था बनाए रखने के लिए। यद्यपि इसका उद्देश्य शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व सुनिश्चित करना था, परंतु व्यवहार में इसने अधिकार क्षेत्र की सीमाओं को लेकर चर्च और राज्य के बीच सदियों लंबे संघर्ष और वैचारिक द्वंद्व की पृष्ठभूमि तैयार की।

87. (D) तुच्छ शोध जिसने महत्वपूर्ण प्रश्नों की उपेक्षा की।
राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान के दौरान यह प्रमुख तर्क दिया गया कि व्यवहारवाद ने वैज्ञानिक पद्धतियों और आँकड़ों पर इतना अधिक ध्यान केंद्रित कर दिया कि उसने राजनीति के वास्तविक और गंभीर प्रश्नों की उपेक्षा कर दी। आलोचकों के अनुसार, व्यवहारवादी शोध अक्सर तुच्छ और अप्रासंगिक विषयों पर केंद्रित था जिनका सामाजिक कल्याण से कम संबंध था। पुनरुत्थान के समर्थकों ने न्याय, स्वतंत्रता और नैतिकता जैसे 'बड़े प्रश्नों' को पुनः स्थापित करने की मांग की। उन्होंने तर्क दिया कि तकनीक की शुद्धता से अधिक महत्वपूर्ण वह उद्देश्य है जिसके लिए राजनीतिक चिंतन किया जाता है।

88. (A) वितरणात्मक न्याय
प्रगतिशील कराधान प्रणाली वितरणात्मक न्याय का एक व्यावहारिक अनुप्रयोग है, जो यह मानती है कि अधिक आय वाले व्यक्तियों को समाज के प्रति अधिक योगदान देना चाहिए। इस प्रणाली के माध्यम से एकत्र किए गए धन का उपयोग लोक कल्याणकारी योजनाओं और वंचित वर्गों की सहायता के लिए किया जाता है। इसका उद्देश्य समाज में संसाधनों का अधिक न्यायसंगत और संतुलित वितरण सुनिश्चित करना है। वितरणात्मक न्याय का यह सिद्धांत केवल औपचारिक समानता से आगे बढ़कर वास्तविक सामाजिक-आर्थिक समानता की दिशा में कार्य करता है, जिससे समाज की समग्र न्यायपूर्ण संरचना को मजबूती मिलती है।

89. (B) नकारात्मक स्वतंत्रता
सरकार द्वारा बिना किसी कानूनी वारंट के नागरिकों के निजी संचार की जासूसी करना नकारात्मक स्वतंत्रता का एक गंभीर उल्लंघन है। नकारात्मक स्वतंत्रता व्यक्ति के निजी जीवन में बाहरी हस्तक्षेप की अनुपस्थिति पर बल देती है। इसमें निजता का अधिकार एक महत्वपूर्ण घटक है, जो व्यक्ति को राज्य की दमनकारी या अनियंत्रित निगरानी से सुरक्षित रखता है। जब राज्य बिना किसी ठोस आधार के व्यक्ति के निजी दायरे में प्रवेश करता है, तो वह उसकी उस स्वायत्तता को नष्ट कर देता है जो एक स्वतंत्र समाज के लिए अनिवार्य है। यह कृत्य व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति राज्य की निरंकुशता को दर्शाता है।

90. (A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
उत्तर-व्यवहारवाद ने व्यवहारवाद की वैज्ञानिक पद्धतियों को पूरी तरह खारिज नहीं किया, बल्कि उन्हें सामाजिक उद्देश्यों के साथ जोड़ने का प्रयास किया। उन्होंने माना कि आँकड़ा संग्रह और सांख्यिकीय विश्लेषण महत्वपूर्ण हैं, लेकिन वे अपने आप में साध्य नहीं होने चाहिए। उत्तर-व्यवहारवादियों का मुख्य तर्क यह था कि राजनीतिक विज्ञान को 'प्रासंगिक' होना चाहिए और उसे समाज की वास्तविक चुनौतियों का सामना करना चाहिए। अतः उन्होंने अनुभवजन्य शोध की तकनीक को मूल्यों और सामाजिक जिम्मेदारी के एक नए स्तर पर ले जाकर उसे अधिक सार्थक और मानवीय रूप प्रदान करने की वकालत की।

91. (A) एक व्यक्ति को प्रतिनिधित्व के साथ निष्पक्ष सुनवाई प्राप्त होना।
एक व्यक्ति को कानूनी प्रतिनिधित्व के साथ निष्पक्ष सुनवाई प्राप्त होना व्यक्तिगत न्याय का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि कानूनी प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों का सम्मान किया जाए और उसके साथ बिना किसी पक्षपात के व्यवहार हो। व्यक्तिगत न्याय मुख्य रूप से कानून की उचित प्रक्रिया और व्यक्तियों के साथ उनके विशिष्ट मामलों में निष्पक्षता पर केंद्रित होता है। यह अवधारणा इस विश्वास पर आधारित है कि न्याय केवल सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं है, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ किया गया सम्मानजनक और न्यायपूर्ण व्यवहार भी है।

92. (B) नए बाजार और निवेश के अवसर खोजने के लिए।
लेनिन के अनुसार, साम्राज्यवाद पूंजीवाद के विकास का वह चरण है जहाँ एकाधिकारवादी कंपनियां अपने घरेलू बाजारों की सीमाओं से बाहर निकलने को मजबूर हो जाती हैं। पूंजीवादी राष्ट्र अन्य देशों को उपनिवेश इसलिए बनाते हैं ताकि वे अपनी अतिरिक्त पूंजी के लिए नए निवेश क्षेत्र पा सकें, कच्चे माल के स्रोतों पर नियंत्रण कर सकें और अपने माल के लिए नए बाजार ढूंढ सकें। लेनिन ने तर्क दिया कि यह आर्थिक आवश्यकता पूंजीवादी देशों के बीच प्रतिद्वंद्विता और संघर्षों को जन्म देती है, जो अंततः वैश्विक युद्धों और औपनिवेशिक शोषण के चक्र को और अधिक तीव्र करती है।

NODIA

93. (A) चर्च के अधिकारियों की नियुक्ति पर नियंत्रण।
मध्यकाल में पोप और धर्मनिरपेक्ष शासकों के बीच होने वाला पदनियुक्ति विवाद मुख्य रूप से चर्च के महत्वपूर्ण अधिकारियों, जैसे बिशपों और मठाधीशों की नियुक्ति की शक्ति पर केंद्रित था। यह संघर्ष सत्ता के अधिकार क्षेत्र को लेकर था, क्योंकि ये अधिकारी न केवल धार्मिक पदों पर थे, बल्कि उनके पास विशाल भू-संपत्ति और राजनीतिक प्रभाव भी था। राजा चाहते थे कि चर्च पदानुक्रम उनके प्रति वफादार रहे, जबकि चर्च ने इसे अपनी आंतरिक स्वायत्तता और आध्यात्मिक सर्वोच्चता का मुद्दा माना। यह विवाद मध्यकालीन यूरोप के सबसे महत्वपूर्ण चर्च-राज्य संघर्षों में से एक था।

94. (B) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं।
अवसर की समानता का अर्थ केवल 'शुरुआती बिंदु' को समान बनाना नहीं है, बल्कि यह कृत्रिम बाधाओं को दूर कर सभी

को अपनी योग्यता सिद्ध करने का समान मंच प्रदान करने से संबंधित है। वहीं परिणाम की समानता यह सुनिश्चित नहीं करती कि 'प्रयास या प्रतिभा की परवाह किए बिना' सब एक समान हों, बल्कि यह समाज में संसाधनों की अत्यधिक विषमता को कम करने का प्रयास करती है ताकि जीवन की आधारभूत स्थितियाँ समान हों। अतः दोनों अवधारणाओं की यह व्याख्या उनके जटिल स्वरूप को सीमित और गलत तरीके से प्रस्तुत करती है।

95. (B) मन, वचन और कर्म से हिंसा न करना।
गांधीजी के दर्शन में 'अहिंसा' केवल शारीरिक चोट न पहुँचाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक अत्यंत व्यापक और सक्रिय नैतिक सिद्धांत है। इसका अर्थ है मन, वाणी और कर्म तीनों स्तरों पर किसी भी प्राणी के प्रति द्वेष या हानि की भावना न रखना। अहिंसा में दूसरों के प्रति प्रेम, करुणा और सत्य के प्रति समर्पण निहित है। यह कमजोरों का हथियार नहीं, बल्कि आत्मिक रूप से शक्तिशाली व्यक्तियों का मार्ग है। गांधीजी के लिए अहिंसा वह सर्वोच्च शक्ति है जो किसी भी अन्याय के विरुद्ध नैतिक विजय प्राप्त करने में सक्षम है।

96. (C) कोई यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकता कि 'क्या होना चाहिए' केवल 'क्या है' के आधार पर।
व्यवहारवाद के अंतर्गत तथ्य-मूल्य द्विभाजन का अर्थ है कि अनुभवजन्य तथ्यों (क्या है) और मानकीय मूल्यों (क्या होना चाहिए) के बीच एक स्पष्ट सीमा रेखा मौजूद है। वैज्ञानिक जांच को केवल उन तथ्यों तक सीमित रहना चाहिए जिनका परीक्षण किया जा सके, क्योंकि नैतिक निर्णय या मूल्य व्यक्तिपरक होते हैं और उन्हें वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नहीं किया जा सकता। इस तर्क के अनुसार, 'है' के विवरण से 'होना चाहिए' के निर्देश प्राप्त करना तर्कसंगत रूप से असंभव है। यह विभाजन राजनीति विज्ञान को वस्तुनिष्ठ और वैज्ञानिक बनाने की दिशा में एक केंद्रीय प्रयास था।

97. (A) व्यक्तिगत अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रता का संरक्षण।
उदार लोकतंत्र की सबसे प्रमुख विशेषता व्यक्तिगत अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रताओं, जैसे अभिव्यक्ति और सभा की स्वतंत्रता का संवैधानिक संरक्षण है। इसमें बहुमत का शासन तो होता है, लेकिन उसे अल्पसंख्यकों के अधिकारों को दबाने की अनुमति नहीं दी जाती। शक्तियों का पृथक्करण, स्वतंत्र न्यायपालिका और कानून का शासन इसकी अन्य अनिवार्य आधारशिलाएँ हैं। यह व्यवस्था व्यक्ति की स्वायत्तता को सर्वोपरि मानती है और राज्य की शक्ति को सीमित कर नागरिकों के लिए एक सुरक्षित और स्वतंत्र वातावरण सुनिश्चित करने का प्रयास करती है जो लोकतंत्र की आत्मा है।

98. (A) "समानता सुनिश्चित करने के लिए राज्य को उत्पादन का स्वामित्व रखना चाहिए।"
यह कथन एक विचारधारा को दर्शाता है क्योंकि यह न केवल एक समस्या (असमानता) की व्याख्या करता है, बल्कि उसे हल करने के लिए एक विशिष्ट लक्ष्य और कार्ययोजना (राज्य का स्वामित्व) भी प्रस्तुत करता है। विचारधाराएँ तथ्यों के साथ-साथ मूल्यों और आदर्शों का समावेश करती हैं, जो समाज के संगठन के बारे में एक विशिष्ट दृष्टिकोण प्रदान करती हैं। अन्य विकल्प केवल सरल तथ्यात्मक सूचनाएँ हैं, जबकि यह कथन एक राजनीतिक दर्शन और समाजवादी विश्वदृष्टि पर आधारित है, जिसका उद्देश्य समाज की आर्थिक और राजनीतिक संरचना में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना है।

99. (B) अर्ध-सामंती और अर्ध-औपनिवेशिक देश।
माओ जेदोंग की "नई जनवाद" की अवधारणा विशेष रूप से उन देशों के लिए विकसित की गई थी जो अर्ध-सामंती और अर्ध-औपनिवेशिक स्थिति में थे। माओ का तर्क था कि इन देशों में क्रांति का पहला चरण सीधे समाजवाद नहीं, बल्कि विदेशी साम्राज्यवाद और स्थानीय सामंतवाद के विरुद्ध एक व्यापक गठबंधन बनाना होना चाहिए। इसमें किसान, मजदूर और देशभक्त राष्ट्रीय पूंजीपति वर्ग शामिल थे। यह संक्रमणकालीन चरण समाज की उत्पादक शक्तियों को विकसित करने और अंततः पूर्ण समाजवादी क्रांति के लिए आवश्यक आधार और जनसमर्थन तैयार करने की दिशा में एक रणनीतिक कदम था।

100. (B) केवल II और III
मध्यकालीन चर्च और राज्य के संबंध स्थिर नहीं थे, बल्कि वे निरंतर वैचारिक और राजनीतिक संघर्ष के माध्यम से विकसित होते रहे। चर्च के 'शक्ति की पूर्णता' के दावों ने यह तर्क दिया कि पोप के पास आध्यात्मिक और लौकिक दोनों क्षेत्रों में अंतिम अधिकार है, जिससे धर्मनिरपेक्ष शासकों की शक्ति को सीधी चुनौती मिली। इसके उत्तर में, पादुआ के मार्सिलियस जैसे विचारकों ने नागरिक समाज और धर्मनिरपेक्ष राज्य की सर्वोच्चता का बचाव किया। ये विरोधाभासी विचार मध्यकालीन राजनीतिक दर्शन की गहराई और उस काल के तीव्र सत्ता संघर्षों को दर्शाते हैं।

101. (C) मानकीय कथन अर्थहीन हैं क्योंकि उनमें सत्यापन का अभाव है।
तार्किक प्रत्यक्षवाद का तर्क था कि केवल उन्हीं कथनों का कोई वास्तविक अर्थ होता है जिन्हें अनुभवजन्य रूप से सत्यापित किया जा सके। इस दृष्टिकोण ने न्याय, नैतिकता और स्वतंत्रता जैसे मानकीय कथनों को वैज्ञानिक दृष्टि से अप्रासंगिक घोषित कर दिया, क्योंकि वे केवल व्यक्तिपरक भावनाओं को व्यक्त करते थे। इसी विचारधारा के प्रभाव में बीसवीं शताब्दी के मध्य में राजनीतिक सिद्धांत के 'पतन' की बात कही गई, क्योंकि पारंपरिक दार्शनिक चिंतन को 'अवैज्ञानिक' और 'अर्थहीन' मानकर उपेक्षित किया जाने लगा था।

102. (A) राज्य केवल दूसरों को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए हस्तक्षेप कर सकता है।
जॉन स्टुअर्ट मिल द्वारा प्रस्तुत 'क्षति का सिद्धांत' यह प्रतिपादित करता है कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने का एकमात्र उचित आधार दूसरों को होने वाले नुकसान को रोकना है। व्यक्ति का अपने स्वयं के शरीर और मस्तिष्क पर पूर्ण अधिकार है। यह सिद्धांत राज्य की दमनकारी शक्तियों को सीमित करता है और यह सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति के निजी कार्यों में तब तक कोई बाधा न डाली जाए जब तक कि वे समाज के अन्य सदस्यों की सुरक्षा को प्रभावित न करें।

Click Here to Buy book on Amazon

103. (C) माओ
"जन-लाइन" माओ जेदोंग द्वारा विकसित एक संगठनात्मक और नेतृत्व सिद्धांत है। इसका मूल मंत्र "जनता से लो और जनता को दो" है। इसके अनुसार, कम्युनिस्ट पार्टी को जनता की असंगठित मांगों और विचारों को एकत्र करना चाहिए, उन्हें मार्क्सवादी सिद्धांतों के आधार पर व्यवस्थित करना चाहिए और फिर उन्हें नीतियों के रूप में वापस जनता के पास ले जाना चाहिए। यह सिद्धांत पार्टी और आम लोगों के बीच निरंतर संवाद सुनिश्चित करता है ताकि क्रांति की जड़ें समाज में गहराई तक बनी रहें।

104. (B) शास्त्रीय उदारवाद के सिद्धांत।
व्यक्तिगत न्याय का मूल विचार शास्त्रीय उदारवाद से गहराई से जुड़ा है, जो व्यक्ति की स्वायत्तता, कानून के समक्ष समानता और संपत्ति के अधिकार को सर्वोपरि मानता है। यह दृष्टिकोण समाज को स्वतंत्र व्यक्तियों के समूह के रूप में देखता है जहाँ न्याय का अर्थ प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना और निष्पक्ष कानूनी प्रक्रिया सुनिश्चित करना है। व्यक्तिगत न्याय सामूहिक लक्ष्यों के बजाय व्यक्ति के साथ होने वाले तर्कसंगत और निष्पक्ष व्यवहार पर केंद्रित रहता है, जो आधुनिक लोकतांत्रिक प्रणालियों का एक अनिवार्य आधार है।

105. (B) परंपरावाद और व्यवहारवाद का संश्लेषण।
उत्तर-व्यवहारवाद को परंपरावाद और व्यवहारवाद के संश्लेषण के रूप में देखा जा सकता है। इसने व्यवहारवाद की वैज्ञानिक और अनुभवजन्य पद्धतियों को पूर्णतः त्यागा नहीं, बल्कि उन्हें परंपरावाद की मूल्य-आधारित और मानकीय चिंताओं के साथ जोड़ने का प्रयास किया। उत्तर-व्यवहारवाद ने तर्क दिया कि राजनीति विज्ञान को न केवल वैज्ञानिक होना चाहिए, बल्कि उसे सामाजिक समस्याओं के प्रति प्रासंगिक भी होना चाहिए। इस दृष्टिकोण ने तथ्यों और मूल्यों के बीच के संतुलन को पुनः स्थापित कर अनुशासन को अधिक व्यापक और अर्थपूर्ण बनाया।

106. (A) पुरोहितीय या आध्यात्मिक अधिकार।
मध्यकालीन लैटिन राजनीतिक शब्दावली में 'सेसरडोटियम' शब्द पुरोहितों या चर्च के आध्यात्मिक अधिकार क्षेत्र को संदर्भित करता था। यह शब्द विशेष रूप से पोप और पादरियों की उस शक्ति के लिए प्रयुक्त होता था जो आत्माओं के कल्याण, धार्मिक अनुष्ठानों और ईश्वरीय कानूनों की व्याख्या से जुड़ी थी। दो तलवारों के सिद्धांत के अंतर्गत इसे 'आध्यात्मिक तलवार' माना गया, जो शाही अधिकार से भिन्न थी। सेसरडोटियम और शाही अधिकार के बीच का यह विभाजन मध्ययुगीन यूरोप में सत्ता के द्वंद्व का मुख्य आधार था।

107. (A) शासन के संस्थानों और नियमों पर जोर देने वाली प्रणाली।
प्रक्रियात्मक लोकतंत्र मुख्य रूप से शासन की उन विधियों और औपचारिक संस्थानों पर केंद्रित होता है जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को संचालित करते हैं। इसमें स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, सार्वभौमिक मताधिकार और कानून के शासन जैसे तत्वों को प्राथमिक माना जाता है। यह दृष्टिकोण इस विचार पर आधारित है कि यदि निर्णय लेने की प्रक्रिया न्यायसंगत और नियमबद्ध है, तो शासन का स्वरूप लोकतांत्रिक बना रहेगा। हालाँकि, यह हमेशा परिणामों की समानता या सामाजिक न्याय की पूर्ण गारंटी नहीं देता, बल्कि केवल चुनावी ढांचे की शुद्धता सुनिश्चित करता है।

108. (D) अभिजात वर्ग की समानता
समानता की अवधारणा सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और अवसर सुनिश्चित करने से संबंधित है, जबकि 'अभिजात वर्ग की समानता' जैसा कोई औपचारिक रूप राजनीतिक सिद्धांत में स्वीकार्य नहीं है। राजनीतिक सिद्धांत मुख्य रूप से कानूनी, राजनीतिक और सामाजिक समानता पर बल देता है ताकि समाज के प्रत्येक सदस्य को बिना किसी भेदभाव के समान दर्जा प्राप्त हो सके। अभिजात वर्ग की अवधारणा स्वाभाविक रूप से विशेषाधिकार और असमानता पर आधारित होती है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों और समानता के सार्वभौमिक सिद्धांतों के पूर्णतः विपरीत है।

109. (C) आर्थिक आत्मनिर्भरता।
गांधीजी की 'स्वदेशी' की अवधारणा मुख्य रूप से आर्थिक आत्मनिर्भरता और स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देने से संबंधित है। इसका उद्देश्य विदेशी वस्तुओं पर निर्भरता कम करना और ग्रामोद्योगों को पुनर्जीवित करना था ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके। स्वदेशी केवल एक आर्थिक नीति नहीं थी, बल्कि यह आत्म-सम्मान और स्वावलंबन का एक व्यापक दर्शन था। गांधीजी का मानना था कि जब तक भारत आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं होगा, तब तक उसकी राजनीतिक स्वतंत्रता अधूरी और अस्थिर बनी रहेगी।

110. (A) P-3, Q-4, R-2, S-1
तथ्य-मूल्य द्विभाजन व्यवहारवाद की मुख्य विशेषता है जो वैज्ञानिक शोध को मूल्यों से अलग रखने पर बल देती है। 'शक्ति की पूर्णता' मध्यकालीन पापल सिद्धांत से संबंधित है जो पोप की असीमित शक्ति का दावा करता है। सत्याग्रह गांधीवादी संघर्ष का मुख्य आधार है जो अहिंसक प्रतिरोध पर केंद्रित है। 'प्रासंगिकता का सिद्धांत' उत्तर-व्यवहारवाद द्वारा प्रस्तुत किया गया था जिसने शोध को सामाजिक समस्याओं के समाधान हेतु सार्थक बनाने का आह्वान किया। ये चारों अवधारणाएं राजनीतिक चिंतन के विभिन्न युगों और आंदोलनों की विशिष्ट पहचान को स्पष्ट करती हैं।

111. (D) औपचारिक समानता गहरी सामाजिक असमानताओं को दूर करने में विफल रही।
सामाजिक न्याय की मांग इस ऐतिहासिक अनुभव से उत्पन्न हुई कि कानून के समक्ष केवल औपचारिक समानता समाज में व्याप्त गहरी जातिगत, आर्थिक और लैंगिक खाइयों को पाटने के लिए पर्याप्त नहीं है। समाज के वंचित वर्गों को वास्तव में समान मंच प्रदान करने के लिए राज्य द्वारा विशेष प्रयासों और संसाधनों के पुनर्वितरण की आवश्यकता महसूस की गई। सामाजिक न्याय का उद्देश्य उन संरचनात्मक बाधाओं को हटाना है जो लोगों को उनके अधिकारों का वास्तविक लाभ लेने से रोकती हैं, जिससे एक अधिक न्यायपूर्ण और समावेशी समाज का निर्माण हो सके।

Downloaded from www.pdf.tube

112. (B) बुर्जुआ वर्ग लोकतांत्रिक क्रांति के लिए बहुत कमजोर था।
लेनिन ने तर्क दिया कि रूस में बुर्जुआ वर्ग ऐतिहासिक रूप से इतना कमजोर और डरा हुआ था कि वह राजशाही के विरुद्ध एक सफल लोकतांत्रिक क्रांति का नेतृत्व नहीं कर सकता था। इसलिए, उन्होंने माना कि सर्वहारा वर्ग को किसान वर्ग के साथ मिलकर सीधे समाजवादी क्रांति की ओर बढ़ना चाहिए। यह लेनिनवादी सिद्धांत मार्क्स के पारंपरिक विकासवादी चरणों की व्याख्या से एक महत्वपूर्ण विचलन था, जिसने पिछड़े देशों में भी साम्यवादी क्रांति की संभावना और उसकी आवश्यकता को सैद्धांतिक रूप से सिद्ध करने का कार्य किया।

113. (C) सापेक्षवाद
राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान के दौरान सापेक्षवाद की कड़ी आलोचना की गई, जिसने यह तर्क दिया था कि सभी मूल्य और सिद्धांत केवल संस्कृति और समय पर आधारित होते हैं और कोई सार्वभौमिक सत्य नहीं है। पुनरुत्थान के समर्थकों ने माना कि सापेक्षवाद ने न्याय और नैतिकता जैसे मौलिक मूल्यों की जड़ों को कमजोर कर दिया है। उन्होंने न्याय और अधिकारों के लिए सार्वभौमिक मानकीय आधारों की खोज पर फिर से बल दिया। इस वैचारिक परिवर्तन ने राजनीतिक दर्शन को एक ठोस नैतिक धरातल प्रदान किया, जिससे सिद्धांतों की पुनः प्रतिष्ठा संभव हुई।

114. (C) आध्यात्मिक और लौकिक अधिकार के बीच के विभाजन का वर्णन करने के लिए।
'दो तलवारों का सिद्धांत' एक प्रसिद्ध रूपक था जिसका उपयोग मध्यकालीन यूरोप में यह समझाने के लिए किया गया कि ईश्वर ने दुनिया के शासन के लिए दो अलग-अलग सत्ताओं को नियुक्त किया है। इसमें आध्यात्मिक तलवार चर्च और पोप के पास आत्माओं के कल्याण के लिए होती है, जबकि लौकिक तलवार राजाओं और सम्राटों के पास सांसारिक व्यवस्था और रक्षा के लिए होती है। यह सिद्धांत मध्ययुगीन समाज के संगठनात्मक ढांचे को स्पष्ट करता था जहाँ धर्म और राजनीति एक-दूसरे के पूरक तो थे, परंतु उनके अधिकार क्षेत्र अलग-अलग माने जाते थे।

115. (A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
उदार लोकतंत्र में बहुमत का शासन अनिवार्य है, लेकिन वह कभी भी निरपेक्ष या असीमित नहीं होता। संवैधानिक सीमाएँ और कानून का शासन यह सुनिश्चित करते हैं कि बहुमत की शक्ति का उपयोग अल्पसंख्यकों के मौलिक अधिकारों को दबाने के लिए न किया जाए। उदारवादी सिद्धांतों के अनुसार, सरकार की शक्तियों पर नियंत्रण और नागरिकों की स्वतंत्रताओं का संरक्षण लोकतंत्र की आधारशिला है। अतः बहुमत और अल्पसंख्यकों के बीच का यह संतुलन ही एक व्यवस्था को केवल चुनावी शासन के बजाय वास्तव में उदार लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाता है।

116. (B) कार्य के माध्यम से एक बेहतर समाज बनाने में संलग्न होना चाहिए।
उत्तर-व्यवहारवाद में 'कार्य' पर जोर देने का सीधा अर्थ था कि राजनीतिक वैज्ञानिकों को केवल निष्पक्ष पर्यवेक्षक बनकर नहीं रहना चाहिए। उनकी यह नैतिक जिम्मेदारी है कि वे अपने वैज्ञानिक ज्ञान और शोध का उपयोग समाज की बुराइयों को दूर करने और एक न्यायपूर्ण समाज के निर्माण के लिए करें। शोध का अंतिम लक्ष्य केवल प्रकाशन नहीं, बल्कि सामाजिक सुधार और परिवर्तन होना चाहिए। यह दृष्टिकोण विद्वानों को सामाजिक संकटों के समय अपनी सक्रिय भूमिका निभाने और मानवता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को सिद्ध करने के लिए निरंतर प्रेरित करता है।

NODIA

117. (C) रुढ़िवादी
रुढ़िवादी विचारधारा का मुख्य उद्देश्य समाज की मौजूदा संस्थाओं, परंपराओं और मूल्यों को संरक्षित करना होता है। रुढ़िवादी विचारक परिवर्तन के प्रति संशयवादी होते हैं और उनका मानना है कि अचानक या क्रांतिकारी बदलाव समाज की स्थिरता और व्यवस्था को नष्ट कर सकते हैं। वे क्रमिक और ऐतिहासिक अनुभव पर आधारित सुधारों को प्राथमिकता देते हैं। यह विचारधारा समाज के जैविक विकास और अतीत की संचित बुद्धि के प्रति सम्मान प्रकट करती है, जिससे स्थापित सामाजिक और राजनीतिक संरचनाओं को सुरक्षा और निरंतरता प्राप्त होती है।

118. (B) सामाजिक न्याय
सामाजिक न्याय की अवधारणा व्यक्तिगत आचरण के स्थान पर समाज की बुनियादी संरचना, उसके संस्थानों और संसाधनों के वितरण के नियमों की निष्पक्षता पर ध्यान केंद्रित करती है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि समाज के लाभों और बोझों का वितरण इस प्रकार हो कि किसी भी वर्ग के साथ ऐतिहासिक या संरचनात्मक भेदभाव न हो। सामाजिक न्याय यह मानता है कि व्यक्तिगत प्रयास केवल तभी फलदायी हो सकते हैं जब सामाजिक परिवेश न्यायपूर्ण हो। अतः यह व्यवस्थागत असमानताओं को दूर कर एक निष्पक्ष सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने की वकालत करता है।

119. (C) लंबी अवधि का जनयुद्ध
माओवाद की एक प्रमुख विशेषता 'लंबी अवधि का जनयुद्ध' का सिद्धांत है। माओ ने तर्क दिया कि चीन जैसे पिछड़े और कृषि प्रधान देशों में क्रांति एक झटके में नहीं, बल्कि ग्रामीण इलाकों में जनसमर्थन और गुरिल्ला युद्ध के माध्यम से धीरे-धीरे शहरों को घेरने से ही सफल हो सकती है। इसमें किसानों की लामबंदी और उनके साथ गहरे संबंध अनिवार्य माने गए। यह सिद्धांत न केवल सैन्य रणनीति है, बल्कि यह जनता को राजनीतिक रूप से जागरूक करने और क्रांतिकारी चेतना के विस्तार का एक दीर्घकालिक सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रम भी है।

120. (B) 2, 1, 3
कालानुक्रमिक दृष्टि से, पोप जेलासियस प्रथम का पत्र "दुओ सुंट" पाँचवीं शताब्दी के अंत (494 ईस्वी) में लिखा गया था, जिसने मध्यकालीन दो तलवारों के सिद्धांत की नींव रखी। इसके बहुत बाद, 1902 में लेनिन की प्रसिद्ध रचना "क्या किया जाना चाहिए?" प्रकाशित हुई, जिसने बोल्शेविक क्रांति के संगठनात्मक ढांचे को परिभाषित किया। अंत में, 1969 में

डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद की आलोचना करते हुए उत्तर-व्यवहारवाद के आगमन की घोषणा की। यह क्रम मध्यकाल से लेकर आधुनिक राजनीति विज्ञान के वैचारिक विकास के महत्वपूर्ण पड़ावों को सही ढंग से दर्शाता है।

121. (A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।
स्वतंत्रता की दो अवधारणाओं के बीच का अंतर अत्यंत महत्वपूर्ण है। नकारात्मक स्वतंत्रता मुख्य रूप से व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंधों और दूसरों के हस्तक्षेप के अभाव पर बल देती है, जिसे 'से स्वतंत्रता' कहा जाता है। इसके विपरीत, सकारात्मक स्वतंत्रता व्यक्ति की उन आंतरिक क्षमताओं और परिस्थितियों के विकास से संबंधित है जो उसे अपना सर्वश्रेष्ठ स्वरूप प्राप्त करने में सक्षम बनाती हैं, जिसे 'की स्वतंत्रता' माना जाता है। अतः यह दोनों कथन स्वतंत्रता के व्यक्तिवादी और विकासात्मक आयामों को प्रभावी ढंग से स्पष्ट करते हैं, जो आधुनिक राजनीतिक चिंतन के आधार हैं।

122. (B) चर्च और राज्य के लिए अलग-अलग क्षेत्रों को परिभाषित करना।
पोप जेलासियस प्रथम द्वारा प्रस्तुत दो तलवारों के सिद्धांत का प्राथमिक उद्देश्य चर्च और राज्य की शक्तियों के मध्य अधिकार क्षेत्र की स्पष्ट सीमाएँ निर्धारित करना था। उनका तर्क था कि ईश्वर ने मानव जीवन के दो अलग-अलग पहलुओं के लिए दो स्वतंत्र सत्ताओं की स्थापना की है: आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए चर्च और सांसारिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए धर्मनिरपेक्ष शासक। यह सिद्धांत दोनों सत्ताओं के बीच सहयोग और संतुलन स्थापित करने का एक प्रारंभिक प्रयास था ताकि वे एक-दूसरे के आवश्यक कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप किए बिना कार्य कर सकें।

123. (C) तथ्य और मूल्य का पृथक्करण
व्यवहारवाद का एक केंद्रीय सिद्धांत तथ्यों और मूल्यों के बीच स्पष्ट पृथक्करण सुनिश्चित करना है। व्यवहारवादियों का मानना था कि राजनीति विज्ञान को केवल उन अवलोकनीय और सत्यापन योग्य तथ्यों तक सीमित रहना चाहिए जिनका वैज्ञानिक रूप से अध्ययन किया जा सके। मानकीय मूल्यों और नैतिक निर्णयों को व्यक्तिगत और व्यक्तिपरक मानकर उन्हें वैज्ञानिक जांच के दायरे से बाहर रखा गया। इस 'मूल्य-तटस्थता' के माध्यम से अनुशासन को अधिक वस्तुनिष्ठ बनाने का प्रयास किया गया, जिससे राजनीति का अध्ययन प्राकृतिक विज्ञानों के समान अधिक वैज्ञानिक और भविष्योन्मुखी बन सके।

124. (C) विकेंद्रीकृत गांवों पर आधारित एक राज्यविहीन समाज।
गांधीजी का आदर्श समाज 'रामराज्य' एक ऐसा राज्यविहीन समाज है जहाँ प्रत्येक व्यक्ति अपना स्वयं का शासक होता है। वे केंद्रीकृत राज्य सत्ता को हिंसा का प्रतीक मानते थे, इसलिए उन्होंने विकेंद्रीकृत ग्राम गणराज्यों की वकालत की। उनके अनुसार, वास्तविक लोकतंत्र तभी संभव है जब सत्ता और संसाधनों का नियंत्रण स्थानीय समुदायों और गांवों के हाथ में हो। यह दृष्टिकोण 'स्वराज' और 'सर्वोदय' के सिद्धांतों पर आधारित है, जो शोषण मुक्त, आत्मनिर्भर और नैतिक रूप से जागरूक समुदायों के एक संघ के रूप में समाज की कल्पना करता है।

125. (A) केवल III
राजनीतिक समानता लोकतांत्रिक सिद्धांत का सबसे अनिवार्य केंद्र है, जो प्रत्येक नागरिक को शासन की प्रक्रिया में समान भागीदारी और वोट का समान मूल्य प्रदान करती है। यद्यपि कई लोकतांत्रिक देशों में पूंजीवाद है, परंतु यह लोकतंत्र के लिए एक अनिवार्य शर्त नहीं है क्योंकि समाजवादी लोकतंत्र भी अस्तित्व में हैं। इसके अतिरिक्त, प्रत्यक्ष लोकतंत्र बड़े और आधुनिक जटिल राष्ट्रों में व्यावहारिक नहीं है, जिसके कारण प्रतिनिधि लोकतंत्र को अधिक प्रभावी माना जाता है। अतः कथन III ही लोकतंत्र के सार्वभौमिक और मूलभूत आदर्श को पूरी तरह सत्य रूप में व्यक्त करता है।

126. (B) जॉन रॉल्स द्वारा "न्याय का सिद्धांत"
1971 में जॉन रॉल्स की पुस्तक "न्याय का सिद्धांत" के प्रकाशन को राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान में एक मील का पत्थर माना जाता है। इस पुस्तक ने न्याय, निष्पक्षता और अधिकारों के बारे में दार्शनिक बहस को पुनः जीवित किया और व्यवहारवाद की वैज्ञानिक शुष्कता के कारण आई स्थिरता को समाप्त किया। रॉल्स ने एक न्यायपूर्ण समाज के लिए ठोस नैतिक आधार प्रदान किए, जिससे राजनीतिक चिंतन में मानकीय प्रश्नों का महत्व फिर से स्थापित हुआ। इस रचना ने न केवल अकादमिक जगत को प्रभावित किया, बल्कि इसने आधुनिक उदारवादी लोकतंत्र के लिए एक नई वैचारिक दिशा भी निर्धारित की।

127. (C) श्रमिक स्वतःस्फूर्तता केवल ट्रेड यूनियनवाद की ओर ले जाएगी।
लेनिन का अग्रगामी दल का सिद्धांत इस विश्वास पर आधारित था कि श्रमिक वर्ग स्वयं केवल 'ट्रेड-यूनियन चेतना' विकसित कर सकता है, जो केवल वेतन और काम की परिस्थितियों में सुधार तक सीमित होती है। लेनिन ने तर्क दिया कि पूंजीवाद को उखाड़ फेंकने के लिए एक उच्च राजनीतिक चेतना की आवश्यकता है, जो केवल बाहर से एक अनुशासित और पेशेवर क्रांतिकारियों की पार्टी द्वारा ही दी जा सकती है। अतः अग्रगामी दल का कार्य श्रमिकों को संगठित करना और उन्हें क्रांतिकारी संघर्ष के लिए आवश्यक दिशा एवं नेतृत्व प्रदान करना है ताकि वास्तविक परिवर्तन संभव हो सके।

128. (B) सार्वजनिक शिक्षा के लिए प्रगतिशील कराधान लागू करना।
सामाजिक न्याय के समर्थक ऐसी नीतियों की वकालत करते हैं जो संसाधनों का न्यायसंगत पुनर्वितरण सुनिश्चित करें। सार्वजनिक शिक्षा के लिए प्रगतिशील कराधान लागू करना इसका सटीक उदाहरण है, क्योंकि यह अधिक संपन्न लोगों से अधिक योगदान लेता है और उन संसाधनों का उपयोग समाज के वंचित वर्गों को समान अवसर प्रदान करने के लिए करता है। शिक्षा के माध्यम से योग्यता विकसित करने के समान अवसर प्रदान करना सामाजिक न्याय की दिशा में एक बुनियादी कदम है। यह नीति समाज की संरचनात्मक असमानताओं को

Click Here to Buy book on Amazon

कम करने और एक समावेशी भविष्य की नींव रखने के लिए आवश्यक मानी जाती है।

129. (B) शहरी सर्वहारा बनाम ग्रामीण किसान वर्ग की भूमिका।
लेनिन और माओ के क्रांति सिद्धांतों के बीच सबसे मौलिक अंतर क्रांतिकारी वर्ग की पहचान में निहित है। लेनिन ने औद्योगिक शहरी सर्वहारा वर्ग को क्रांति का नेतृत्वकर्ता माना, जो मार्क्सवादी सिद्धांतों के अनुरूप था। इसके विपरीत, माओ ने चीनी परिस्थितियों को देखते हुए ग्रामीण किसान वर्ग को क्रांति की मुख्य और प्राथमिक शक्ति के रूप में स्थापित किया। जहाँ लेनिन की रणनीति शहरी विद्रोहों पर केंद्रित थी, वहीं माओ ने "गांवों द्वारा शहरों को घेरने" की रणनीति अपनाई। यह विचलन मार्क्सवाद के इतिहास में एक महत्वपूर्ण वैचारिक विस्तार और रूपांतरण माना जाता है।

130. (B) चर्च-राज्य संबंधों का एक सहकारी दृष्टिकोण।
मध्यकालीन विचार कि राज्य का मुख्य कार्य शांति और व्यवस्था बनाए रखना है ताकि चर्च बिना किसी बाधा के लोगों का आध्यात्मिक मार्गदर्शन कर सके, दोनों सत्ताओं के बीच एक सहकारी दृष्टिकोण को दर्शाता है। इसमें राज्य और चर्च को एक ही ईसाई समाज के दो अभिन्न अंगों के रूप में देखा गया, जिनके लक्ष्य अलग थे लेकिन वे एक-दूसरे की सफलता के लिए अनिवार्य थे। राज्य को चर्च के 'लौकिक हाथ' के रूप में देखा गया, जो धर्म की रक्षा और समाज में नैतिकता सुनिश्चित करने के लिए भौतिक शक्ति का प्रयोग करता था।

131. (D) यह एक विशुद्ध वस्तुनिष्ठ और वैज्ञानिक विवरण है।
विचारधारा कभी भी विशुद्ध रूप से वस्तुनिष्ठ या पूरी तरह वैज्ञानिक नहीं होती, क्योंकि इसमें अनिवार्य रूप से व्यक्तिपरक मूल्यों, लक्ष्यों और भविष्य की आकांक्षाओं का समावेश होता है। यद्यपि विचारधाराएँ वर्तमान समाज की एक सुसंगत व्याख्या प्रदान करती हैं और परिवर्तन के लिए एक स्पष्ट कार्यक्रम प्रस्तुत करती हैं, परंतु वे हमेशा एक विशिष्ट दृष्टिकोण या पक्ष का प्रतिनिधित्व करती हैं। विचारधारा का उद्देश्य केवल दुनिया का वर्णन करना नहीं, बल्कि उसे एक विशेष दिशा में बदलना या संरक्षित करना होता है, जो इसे केवल एक तटस्थ वैज्ञानिक विवरण से अलग और अधिक जटिल बनाता है।

132. (C) इतिहासवाद और प्रत्यक्षवाद की शक्तियों से।
राजनीतिक सिद्धांत के पतन के शोध प्रबंध के अनुसार, इतिहासवाद और प्रत्यक्षवाद वे प्रमुख बौद्धिक प्रवृत्तियाँ थीं जिन्होंने शास्त्रीय सिद्धांत निर्माण की परंपरा को नष्ट किया। इतिहासवाद ने मूल्यों को केवल उनके कालखंड के सापेक्ष मान लिया, जिससे सार्वभौमिक सत्य की खोज समाप्त हो गई। प्रत्यक्षवाद ने केवल अनुभवजन्य रूप से सत्यापन योग्य तथ्यों को स्वीकार किया और मानकीय प्रश्नों को 'अवैज्ञानिक' मानकर खारिज कर दिया। इन दोनों के प्रभाव में राजनीतिक चिंतन ने अपनी दार्शनिक गहराई खो दी और वह केवल आँकड़ों के संचय और ऐतिहासिक वर्णनों तक सीमित होकर रह गया।

133. (B) इसके लिए स्थिति की अंतर्निहित असमानताओं को दूर करने की आवश्यकता है।
अवसर की समानता की अवधारणा की आलोचना अक्सर इस आधार पर की जाती है कि यह समाज में पहले से मौजूद गहरी संरचनात्मक और आर्थिक असमानताओं की उपेक्षा करती है। आलोचकों का तर्क है कि जब तक लोगों के शुरुआती बिंदु समान नहीं होंगे, तब तक केवल कृत्रिम बाधाओं को हटाना वास्तविक समानता प्रदान नहीं कर सकता। अतः केवल 'एक समान मैदान' प्रदान करना पर्याप्त नहीं है; इसके लिए उन सामाजिक विषमताओं को सक्रिय रूप से दूर करना अनिवार्य है जो कुछ लोगों को प्रतिस्पर्धा में स्वाभाविक रूप से लाभ प्रदान करती हैं।

134. (B) सामाजिक समस्याओं के लिए शोध की अधिक प्रासंगिकता।
उत्तर-व्यवहारवादी आंदोलन की सबसे प्रमुख और केंद्रीय मांग यह थी कि राजनीति विज्ञान के शोध को समाज की वास्तविक और तत्कालीन समस्याओं के प्रति अधिक प्रासंगिक होना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि केवल अकादमिक उद्देश्यों के लिए आँकड़े एकत्र करना और तकनीकी शुद्धता प्राप्त करना पर्याप्त नहीं है, विशेषकर तब जब समाज संकटों से जूझ रहा हो। उत्तर-व्यवहारवाद ने यह संदेश दिया कि विद्वानों को अपने ज्ञान का उपयोग नस्लवाद, युद्ध और गरीबी जैसी ज्वलंत समस्याओं को हल करने के लिए करना चाहिए। "प्रासंगिकता" ही इस आंदोलन का मुख्य नारा और उसकी वैचारिक पहचान बनी।

135. (A) P-4, Q-1, R-2, S-3
यशायाह बर्लिन ने स्वतंत्रता की अपनी प्रसिद्ध व्याख्या में नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता के बीच मौलिक अंतर को स्पष्ट किया। जॉन रॉल्स ने न्याय के सिद्धांत को आधुनिक राजनीतिक दर्शन के केंद्र में पुनः स्थापित किया। मिशेल फौकॉल्ट ने शक्ति और ज्ञान के बीच के गहरे संबंधों का विश्लेषण किया, जिससे राजनीति को समझने का एक नया दृष्टिकोण मिला। लेनिन ने क्रांति को सफल बनाने के लिए एक अनुशासित और पेशेवर क्रांतिकारियों के 'अग्रगामी दल' की भूमिका पर बल दिया। ये चारों विचारक आधुनिक राजनीतिक चिंतन के विभिन्न आयामों को गहराई से स्पष्ट करते हैं।

136. (C) प्रक्रियात्मक न्याय
निष्पक्ष सुनवाई का व्यक्ति का अधिकार, जिसमें निर्दोषता का अनुमान और कानूनी प्रतिनिधित्व शामिल है, प्रक्रियात्मक न्याय की श्रेणी में आता है। यह अवधारणा इस विश्वास पर आधारित है कि न्याय केवल परिणाम में नहीं, बल्कि उसे प्राप्त करने के लिए अपनाई गई प्रक्रियाओं की निष्पक्षता और शुद्धता में भी निहित है। यदि कानून की उचित प्रक्रिया का कड़ाई से पालन किया जाता है, तो माना जाता है कि व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा हुई है। यह उदारवादी न्याय प्रणाली का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है जो नागरिकों को राज्य की मनमानी से सुरक्षा प्रदान करता है।

NODIA

137. (C) राजनीतिक और आर्थिक विकेंद्रीकरण
गांधीजी की 'ग्राम स्वराज' की अवधारणा राजनीतिक और आर्थिक शक्ति के व्यापक विकेंद्रीकरण के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। उनका मानना था कि भारत की आत्मा उसके गांवों में बसती है और वास्तविक स्वतंत्रता तभी प्राप्त होगी जब प्रत्येक गांव आत्मनिर्भर और स्वशासी इकाई के रूप में विकसित होगा। यह दृष्टिकोण भारी औद्योगिकीकरण और केंद्रीकृत योजना के विरुद्ध है, क्योंकि ये व्यवस्थाएँ व्यक्ति की स्वायत्तता को कम करती हैं। ग्राम स्वराज एक ऐसे समाज की कल्पना करता है जहाँ निर्णय स्थानीय स्तर पर लिए जाएं और आर्थिक संसाधन भी विकेंद्रीकृत हों।

138. (B) मानकीय प्रश्नों में नए सिरे से रुचि।
राजनीतिक सिद्धांत के पतन के दावे को बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में न्याय, अधिकार और स्वतंत्रता जैसे मानकीय प्रश्नों में नए सिरे से पैदा हुई गहरी रुचि के माध्यम से चुनौती दी गई। व्यवहारवाद के दौर में इन विषयों को उपेक्षित कर दिया गया था, परंतु जॉन रॉल्स और अन्य विचारकों के कार्यों ने यह सिद्ध किया कि राजनीति के नैतिक आधारों पर चर्चा करना अनिवार्य है। इस "पुनरुत्थान" ने राजनीतिक चिंतन को फिर से उसकी शास्त्रीय जड़ों से वापस जोड़ा और यह स्थापित किया कि समाज के उद्देश्यों और मूल्यों के बारे में बहस करना ही राजनीति विज्ञान का वास्तविक केंद्र है।

139. (A) शत्रुओं के विरुद्ध देशभक्त वर्गों के साथ सर्वहारा वर्ग को एकजुट करना।
माओवादी सिद्धांत में "संयुक्त मोर्चा" एक महत्वपूर्ण रणनीतिक उपकरण है जिसका उद्देश्य मुख्य शत्रु के विरुद्ध समाज के विभिन्न क्रांतिकारी और देशभक्त वर्गों को एक साथ लाना है। माओ ने तर्क दिया कि साम्राज्यवाद और सामंतवाद जैसे बड़े खतरों से निपटने के लिए सर्वहारा वर्ग को किसानों, बुद्धिजीवियों और यहाँ तक कि राष्ट्रीय पूंजीपतियों के साथ भी सहयोग करना चाहिए। यह मोर्चा क्रांति के आधार को व्यापक बनाता है और आंतरिक मतभेदों को गौण मानकर साझा राष्ट्रीय और सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जनशक्ति को संगठित करने में अत्यंत प्रभावी सिद्ध होता है।

140. (A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
व्यवहारवादी दृष्टिकोण ने राजनीति विज्ञान को एक वस्तुनिष्ठ और वैज्ञानिक अनुशासन बनाने के लिए 'मूल्य-तटस्थता' पर अत्यधिक बल दिया। उनका मानना था कि एक वैज्ञानिक को अपनी जांच के दौरान व्यक्तिगत नैतिक धारणाओं और आदर्शों को अलग रखना चाहिए। व्यवहारवादियों के अनुसार, केवल उन्हीं कथनों को स्वीकार किया जाना चाहिए जिन्हें अवलोकनीय आँकड़ों के माध्यम से अनुभवजन्य रूप से सत्यापित किया जा सके। इस दृष्टिकोण ने राजनीति के अध्ययन में सांख्यिकीय पद्धतियों और परिमाणीकरण के प्रयोग को बढ़ावा दिया ताकि निष्कर्षों में वैज्ञानिक शुद्धता और निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सके।

141. (A) पापल सर्वोच्चता का सिद्धांत
वह सिद्धांत जो यह दावा करता है कि पोप के पास आध्यात्मिक और लौकिक दोनों क्षेत्रों में अंतिम अधिकार है, 'पापल सर्वोच्चता' के रूप में जाना जाता है। इस विचारधारा के अनुसार, सम्राट केवल पोप से प्राप्त अधिकार के आधार पर शासन करते हैं और पोप को राजाओं को नियुक्त करने या पदच्युत करने की शक्ति प्राप्त है। यह मध्यकालीन यूरोप में चर्च द्वारा अपनी श्रेष्ठता स्थापित करने का चरम प्रयास था। इस सिद्धांत ने चर्च और राज्य के बीच के संघर्ष को और अधिक तीव्र कर दिया, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष शासकों ने अपनी संप्रभुता को सीधे ईश्वर से प्राप्त होने का दावा किया।

142. (C) स्वतंत्रता में जिम्मेदारी निहित है; उच्छृंखलता अनियंत्रित होती है।
राजनीतिक सिद्धांत में स्वतंत्रता और उच्छृंखलता के बीच एक स्पष्ट अंतर है। स्वतंत्रता का अर्थ है नियमों और नैतिक सीमाओं के भीतर कार्य करने की क्षमता, जिसमें दूसरों के अधिकारों के प्रति जिम्मेदारी और सम्मान निहित होता है। इसके विपरीत, उच्छृंखलता का तात्पर्य किसी भी प्रकार के नियंत्रण या कानून के बिना केवल अपनी मनमानी इच्छाओं को पूरा करना है, जो दूसरों को नुकसान पहुँचा सकता है। वास्तविक स्वतंत्रता अराजकता नहीं है, बल्कि यह एक व्यवस्थित समाज का हिस्सा है जहाँ स्वतंत्रता का उपभोग जिम्मेदारी के साथ किया जाता है ताकि समाज में सामंजस्य बना रहे।

143. (B) एक कानून जो प्रभावी रूप से बाल गरीबी को कम करता है।
सारवान लोकतंत्र केवल चुनावी प्रक्रियाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज में न्याय, समानता और लोगों के जीवन स्तर में आने वाले वास्तविक सुधारों पर ध्यान केंद्रित करता है। एक ऐसा कानून जो बाल गरीबी को प्रभावी ढंग से कम करता है, सारवान लोकतंत्र का उत्कृष्ट उदाहरण है क्योंकि यह शासन के वास्तविक और न्यायपूर्ण परिणामों को दर्शाता है। यह केवल इस बात से संतुष्ट नहीं है कि चुनाव हुए, बल्कि यह देखता है कि शासन ने जनता के सबसे कमजोर वर्गों के जीवन में क्या सकारात्मक परिवर्तन किए हैं, जो लोकतंत्र का असली उद्देश्य है।

144. (B) एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के उत्पीड़न का साधन।
लेनिन के अनुसार, राज्य कभी भी समाज के विभिन्न वर्गों के बीच एक तटस्थ मध्यस्थ नहीं होता, बल्कि यह अनिवार्य रूप से एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के दमन और शोषण का एक उपकरण है। पूंजीवादी समाज में राज्य बुर्जुआ वर्ग के हितों की रक्षा करता है और सर्वहारा वर्ग को दबाकर रखता है। लेनिन का मानना था कि क्रांति का उद्देश्य इस पुराने राज्य तंत्र को नष्ट करना और 'सर्वहारा की तानाशाही' स्थापित करना है, जो अंततः समाजवाद की ओर ले जाएगी और एक ऐसी स्थिति पैदा करेगी जहाँ राज्य धीरे-धीरे समाप्त हो जाएगा।

145. (B) व्यक्तिगत न्याय
"कानून की उचित प्रक्रिया" व्यक्तिगत न्याय का एक मौलिक सिद्धांत है, जो यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति के

Downloaded from www.pdf.tube

जीवन, स्वतंत्रता या संपत्ति के अधिकार को केवल स्थापित कानूनी विधियों के माध्यम से ही छीना जा सकता है। यह सिद्धांत राज्य की मनमानी शक्तियों पर अंकुश लगाता है और यह गारंटी प्रदान करता है कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ निष्पक्ष और न्यायसंगत व्यवहार हो। यह उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की आधारशिला है, जहाँ न्यायपालिका नागरिकों के अधिकारों के रक्षक के रूप में कार्य करती है और यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी कानून प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध न हो।

146. (A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।
राजनीतिक सिद्धांत के 'पतन' और 'पुनरुत्थान' की बहस अनुशासन के इतिहास के दो महत्वपूर्ण चरणों को दर्शाती है। बीसवीं शताब्दी के मध्य में मानकीय और दार्शनिक चिंतन की कमी के कारण पतन की बात कही गई, जहाँ शोध केवल आँकड़ों और ऐतिहासिक विवरणों तक सीमित रह गया था। इसके विपरीत, 1970 के दशक के आसपास न्याय, अधिकार और नैतिकता जैसे 'बड़े प्रश्नों' की वापसी ने सिद्धांत का पुनरुत्थान किया। अतः दोनों कथन पूरी तरह सत्य हैं और यह स्पष्ट करते हैं कि राजनीतिक चिंतन कैसे वैज्ञानिक शुष्कता से निकलकर पुनः दार्शनिक गहराई की ओर लौटा।

147. (C) हिंसा का उपयोग
गांधीवादी और माओवादी परिवर्तन के सिद्धांतों के बीच सबसे बड़ा अंतर हिंसा के उपयोग के प्रति उनके दृष्टिकोण में है। गांधीजी का पूरा दर्शन पूर्णतः अहिंसा और सत्य पर आधारित है, जहाँ वे मानते हैं कि हिंसक साधनों से कभी भी एक शांतिपूर्ण और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण नहीं किया जा सकता। इसके विपरीत, माओ जेदोंग का मानना था कि राजनीतिक शक्ति 'बंदूक की नली' से निकलती है और क्रांतिकारी परिवर्तन प्राप्त करने के लिए सशस्त्र संघर्ष और हिंसा एक अनिवार्य माध्यम है। यह वैचारिक अंतर संघर्ष की पूरी पद्धति और साध्य-साधन के प्रति उनकी समझ को प्रभावित करता है।

148. (B) ऐसा समाज जहाँ धार्मिक और राजनीतिक जीवन आपस में जुड़े हुए थे।
मध्यकालीन यूरोप में ईसाई समाज की अवधारणा एक ऐसे एकीकृत समाज की कल्पना थी जहाँ धार्मिक विश्वास और राजनीतिक सत्ता एक-दूसरे से अटूट रूप से जुड़े हुए थे। इसमें समाज के सभी सदस्य एक ही चर्च के अनुयायी थे और राजाओं के शासन को ईश्वर द्वारा निर्देशित माना जाता था। धार्मिक कानून और नागरिक कानून अक्सर एक-दूसरे को प्रभावित करते थे, और चर्च की भूमिका केवल पूजा तक सीमित न होकर सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण थी। यह आधुनिक धर्मनिरपेक्ष राज्य की अवधारणा के पूर्णतः विपरीत एक साझा धार्मिक पहचान पर आधारित व्यवस्था थी।

149. (B) शक्ति संरचनाओं के लिए नैतिक वैधता की भावना उत्पन्न करती है।
एक विचारधारा राजनीतिक व्यवस्था को वैध बनाने का महत्वपूर्ण कार्य करती है, जिसका अर्थ है कि वह शासक वर्ग या व्यवस्था के अस्तित्व के लिए नैतिक और तार्किक आधार प्रदान करती है। यह नागरिकों को यह विश्वास दिलाने का प्रयास करती है कि वर्तमान सत्ता संरचना और उसके नियम सही, न्यायपूर्ण और अनिवार्य हैं। जब लोग किसी विचारधारा को स्वीकार कर लेते हैं, तो वे स्वेच्छा से आज्ञा पालन करते हैं, जिससे व्यवस्था को स्थिरता प्राप्त होती है। वैधीकरण के बिना किसी भी शासन को केवल बल के प्रयोग से लंबे समय तक बनाए रखना लगभग असंभव होता है।

NODIA

150. (D) I, II और III
परिवर्तन के ये तीनों सिद्धांत आधुनिक राजनीति की महत्वपूर्ण वैचारिक धाराओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेनिन ने क्रांति को सफल बनाने के लिए सर्वहारा नेतृत्व और दो चरणों वाली प्रक्रिया पर बल दिया। माओ जेदोंग ने मार्क्सवाद को चीन के कृषि प्रधान समाज के अनुरूप ढालकर किसानों को क्रांति का मुख्य आधार बनाया, जो एक मौलिक वैचारिक विस्तार था। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के माध्यम से समाज के नैतिक पुनर्निर्माण और स्वराज का एक अद्वितीय मार्ग प्रस्तुत किया। अतः ये तीनों कथन इन विचारकों के विशिष्ट योगदान और उनकी क्रांतिकारी रणनीतियों को सही ढंग से परिभाषित करते हैं।

151. (B) इसका उपयोग राज्य के संरक्षकवाद को सही ठहराने के लिए किया जा सकता है।
सकारात्मक स्वतंत्रता की एक प्रमुख आलोचना यह है कि व्यक्ति को "अपने वास्तविक स्वरूप को साकार करने" में मदद करने के नाम पर राज्य उसके जीवन में अत्यधिक हस्तक्षेप कर सकता है। आलोचकों, विशेष रूप से यशायाह बर्लिन का मानना था कि यह अवधारणा राज्य को यह तय करने का अधिकार दे सकती है कि व्यक्ति के लिए क्या अच्छा है, जिससे व्यक्तिगत स्वायत्तता का ह्रास हो सकता है और अधिनायकवाद को बढ़ावा मिल सकता है। राज्य का यह 'संरक्षकवाद' व्यक्ति की अपनी इच्छाओं को गौण मानकर उन पर बाहरी आदर्श थोपने का प्रयास माना जा सकता है।

152. (B) राजनीति विज्ञान को अधिक प्रासंगिक बनाने का।
उत्तर-व्यवहारवादी क्रांति का मुख्य उद्देश्य राजनीति विज्ञान के अध्ययन को समाज की वास्तविक और तत्कालीन समस्याओं के प्रति अधिक प्रासंगिक और सार्थक बनाना था। इस आंदोलन ने तर्क दिया कि व्यवहारवाद की वैज्ञानिक पद्धतियों और आँकड़ों के प्रति अत्यधिक निष्ठा ने अनुशासन को सामाजिक सरोकारों से दूर कर दिया है। उत्तर-व्यवहारवाद ने यह संदेश दिया कि शोध को केवल बौद्धिक कौतूहल के लिए नहीं, बल्कि नस्लवाद, युद्ध और गरीबी जैसे संकटों को सुलझाने के लिए निर्देशित होना चाहिए। यह क्रांति अनुशासन में मूल्यों और सक्रिय सामाजिक भागीदारी को पुनः स्थापित करने का एक ठोस आह्वान थी।

153. (A) आध्यात्मिक और लौकिक शक्तियों के बीच संघर्ष।
पदनियुक्ति विवाद मध्यकालीन यूरोप में आध्यात्मिक और लौकिक सत्ताओं के बीच सत्ता संघर्ष का एक प्रमुख ऐतिहासिक उदाहरण है। यह संघर्ष इस बात पर केंद्रित था कि क्या सम्राट

को चर्च के उच्चाधिकारियों की नियुक्ति करने का अधिकार है। चर्च ने इसे अपनी आंतरिक और आध्यात्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन माना, जबकि राजाओं ने इसे अपनी राजनीतिक संप्रभुता और भूमि नियंत्रण का मुद्दा बनाया। इस विवाद ने यह स्पष्ट कर दिया कि मध्यकालीन समाज में धर्म और राजनीति के अधिकार क्षेत्र कितने गहराई से उलझे हुए थे और उनके बीच वर्चस्व की लड़ाई कितनी तीव्र थी।

154. (B) समाज की बुनियादी संरचना की निष्पक्षता।
सामाजिक न्याय का प्राथमिक ध्यान केवल व्यक्तिगत कार्यों या कानूनी प्रक्रियाओं पर नहीं, बल्कि समाज के संस्थानों और बुनियादी संरचना की समग्र निष्पक्षता पर होता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि समाज में संसाधनों, अवसरों और अधिकारों का वितरण इस प्रकार हो कि कोई भी वर्ग या समूह ऐतिहासिक रूप से वंचित न रहे। सामाजिक न्याय उन व्यापक विषमताओं को दूर करने का प्रयास करता है जो व्यक्तियों की प्रगति में बाधक होती हैं। यह समाज के सभी सदस्यों के लिए एक समान और न्यायपूर्ण धरातल तैयार करने की वकालत करता है ताकि सामूहिक कल्याण संभव हो सके।

155. (C) माओ
"सौ फूलों को खिलने दो" का नारा माओ जेदोंग द्वारा 1950 के दशक के मध्य में शुरू किए गए एक अभियान का हिस्सा था। इसका उद्देश्य बौद्धिक स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करना और जनता को सरकार की नीतियों पर अपनी राय देने के लिए आमंत्रित करना था। माओ का मानना था कि विचारों की विविधता समाजवाद को मजबूत करेगी। हालाँकि, जब आलोचना बहुत तीव्र हो गई, तो इस अभियान को बंद कर दिया गया और इसके स्थान पर 'दक्षिणपंथ विरोधी अभियान' शुरू किया गया। यह घटना चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के इतिहास में बौद्धिक विमर्श और राजनीतिक नियंत्रण के बीच के जटिल संबंधों को दर्शाती है।

156. (C) निर्वाचित अधिकारियों को अपने कार्यों के लिए नागरिकों को जवाब देना होगा।
प्रतिनिधि लोकतंत्र में जवाबदेही का सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि निर्वाचित प्रतिनिधि जनता की इच्छाओं के अनुरूप कार्य करें और अपनी नीतियों तथा निर्णयों के लिए नागरिकों के प्रति उत्तरदायी रहें। जवाबदेही का अर्थ है कि प्रतिनिधियों को अपने कार्यों का स्पष्टीकरण देना होगा और यदि वे जनता की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरते, तो उन्हें चुनावों के माध्यम से हटाया जा सकता है। यह सिद्धांत शासन में पारदर्शिता लाता है और नागरिकों को यह शक्ति प्रदान करता है कि वे अपनी सरकार पर नियंत्रण रख सकें, जो लोकतांत्रिक शासन की एक अनिवार्य शर्त है।

157. (C) मानकीय और दार्शनिक प्रश्नों पर जोर।
व्यवहारवाद की मुख्य विशेषता राजनीति का वैज्ञानिक और अनुभवजन्य अध्ययन करना है, न कि मानकीय और दार्शनिक प्रश्नों पर ध्यान देना। व्यवहारवादियों ने 'क्या है' के अध्ययन को प्राथमिकता दी और 'क्या होना चाहिए' जैसे नैतिक सवालों को वैज्ञानिक जांच के दायरे से बाहर रखा। उन्होंने तथ्यों को मूल्यों से अलग करने पर बल दिया ताकि अनुशासन को अधिक वस्तुनिष्ठ बनाया जा सके। मानकीय और दार्शनिक चिंतन परंपरावादी दृष्टिकोण का हिस्सा था, जिसके विरुद्ध व्यवहारवाद ने एक वैज्ञानिक क्रांति के रूप में स्वयं को स्थापित करने का प्रयास किया था।

158. (A) आधारभूत समानता
आधारभूत समानता की अवधारणा का तर्क है कि सभी मनुष्यों को उनके जन्मजात गुणों के कारण समान सम्मान और समान व्यवहार का अधिकार प्राप्त है, चाहे उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताएँ या परिस्थितियाँ कुछ भी हों। यह इस विश्वास पर आधारित है कि मानवता का साझा तत्व किसी भी व्यक्तिगत अंतर से अधिक महत्वपूर्ण है। यद्यपि आधुनिक चर्चाओं में 'आनुपातिक' या 'परिणाम की समानता' पर अधिक ध्यान दिया जाता है, परंतु आधारभूत समानता नागरिक अधिकारों और सार्वभौमिक मानवीय गरिमा का वह मौलिक धरातल तैयार करती है जिस पर आधुनिक लोकतांत्रिक और कानूनी प्रणालियाँ खड़ी हैं।

159. (A) समाजवादी क्रांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्थितियाँ पैदा कीं।
लेनिन के अनुसार, साम्राज्यवाद पूंजीवाद का वह चरम चरण है जहाँ मुट्ठी भर शक्तिशाली राष्ट्र पूरी दुनिया का शोषण करने लगते हैं। उन्होंने तर्क दिया कि साम्राज्यवाद ने राष्ट्रों के बीच प्रतिद्वंद्विता और युद्धों को जन्म दिया, जिससे पूंजीवादी व्यवस्था कमजोर हुई। लेनिन का मानना था कि साम्राज्यवाद के इस संकट ने दुनिया भर में और विशेष रूप से "सबसे कमजोर कड़ियों" में समाजवादी क्रांति के लिए उपयुक्त अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ और अवसर पैदा किए। उनके लिए साम्राज्यवाद का उदय पूंजीवाद के अंत और विश्वव्यापी साम्यवादी क्रांति के आगमन का पूर्व संकेत था।

160. (B) 2, 3, 1
ऐतिहासिक दृष्टि से, दो तलवारों का सिद्धांत मध्यकालीन यूरोप (लगभग पाँचवीं से चौदहवीं शताब्दी) में चर्च और राज्य के संबंधों को परिभाषित करने के लिए सबसे अधिक प्रमुख था। इसके सदियों बाद, बीसवीं शताब्दी के मध्य में व्यवहारवाद का उदय हुआ, जिसने राजनीति विज्ञान में वैज्ञानिक पद्धतियों और 'तथ्य-मूल्य द्विभाजन' पर बल दिया। अंत में, 1960 के दशक के उत्तरार्ध में व्यवहारवाद की कमियों के विरुद्ध उत्तर-व्यवहारवाद अस्तित्व में आया, जिसने 'प्रासंगिकता के सिद्धांत' को प्रस्तुत किया। यह क्रम राजनीति विज्ञान के प्राचीन से लेकर आधुनिक वैचारिक विकास को सही ढंग से दर्शाता है।

161. (B) क्रांतिकारी विचारधारा
क्रांतिकारी विचारधारा वर्तमान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था की कड़ी आलोचना करती है और उसे पूरी तरह से उखाड़ फेंककर एक मौलिक रूप से भिन्न और नवीन भविष्य के निर्माण का प्रस्ताव देती है। इसका लक्ष्य केवल सतही सुधार करना नहीं, बल्कि समाज की बुनियादी संरचना को बदलना होता है। क्रांतिकारी विचारधाराएँ अक्सर तीव्र संघर्ष और आमूल-चूल परिवर्तन की वकालत करती हैं, क्योंकि उनका मानना होता है कि मौजूदा व्यवस्था में

Click Here to Buy book on Amazon

सुधार करना असंभव है। मार्क्सवाद और माओवाद जैसे दर्शन क्रांतिकारी विचारधाराओं के सबसे प्रभावशाली उदाहरण हैं जिन्होंने वैश्विक इतिहास को गहराई से प्रभावित किया है।

162. (B) सामाजिक न्याय के मुद्दे और राजनीतिक जीवन का उद्देश्य।
राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान को अक्सर व्यवहारवाद की उस विफलता के विरुद्ध प्रतिक्रिया माना जाता है जिसमें उसने सामाजिक न्याय, स्वतंत्रता और मानवीय जीवन के नैतिक उद्देश्यों जैसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की पूरी तरह उपेक्षा की थी। व्यवहारवाद केवल आँकड़ा संचय और तकनीकी प्रक्रियाओं तक सीमित रह गया था, जिससे वह समाज की गहरी समस्याओं का समाधान करने में असमर्थ था। पुनरुत्थान के समर्थकों ने तर्क दिया कि राजनीति विज्ञान को उन मूल्यों की ओर लौटना चाहिए जो समाज को दिशा प्रदान करते हैं। इस बौद्धिक आंदोलन ने अनुशासन को फिर से एक अर्थपूर्ण और नैतिक रूप से जागरूक रूप प्रदान किया।

163. (B) अंतरात्मा को अपील करने के लिए स्वयं कष्ट सहना।
गांधीवादी सत्याग्रह का मूल सिद्धांत यह है कि सत्य की शक्ति के माध्यम से विरोधी के हृदय को परिवर्तित किया जाए। इसमें सत्याग्रही स्वयं कष्ट सहता है और बिना किसी हिंसा या द्वेष के अन्याय का विरोध करता है। गांधीजी का मानना था कि स्वेच्छा से सहा गया कष्ट विरोधी की अंतरात्मा को झकझोर देता है और उसे उसकी गलतियों का एहसास कराता है। यह पद्धति बल प्रयोग के बजाय नैतिक अनुनय पर आधारित है। सत्याग्रह का अंतिम लक्ष्य विजय प्राप्त करना नहीं, बल्कि दोनों पक्षों के लिए सत्य और न्याय की स्थापना करना है।

164. (A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।
न्याय के ये दोनों आयाम अलग-अलग लेकिन परस्पर संबंधित हैं। व्यक्तिगत न्याय मुख्य रूप से कानून की उचित प्रक्रिया, निष्पक्ष सुनवाई और व्यक्तियों के कानूनी अधिकारों की सुरक्षा पर केंद्रित होता है। इसके विपरीत, सामाजिक न्याय का दायरा अधिक व्यापक है और वह समाज के संस्थानों की संरचना तथा संसाधनों और अवसरों के समग्र वितरण की निष्पक्षता से संबंधित है। जहाँ व्यक्तिगत न्याय किसी विशेष मामले में निष्पक्षता सुनिश्चित करता है, वहीं सामाजिक न्याय समाज में मौजूद व्यापक विषमताओं को दूर करने का प्रयास करता है। अतः दोनों कथन न्याय के इन पूरक रूपों को सही ढंग से स्पष्ट करते हैं।

165. (B) P-2, Q-1, R-4, S-3
सारवान लोकतंत्र शासन के वास्तविक परिणामों और लोगों के जीवन की गुणवत्ता में आने वाले सुधारों पर ध्यान केंद्रित करता है। प्रक्रियात्मक लोकतंत्र मुख्य रूप से मतदान और चुनावी प्रक्रियाओं जैसे औपचारिक नियमों की शुद्धता पर बल देता है। नकारात्मक स्वतंत्रता व्यक्ति के कार्यों में किसी भी प्रकार की बाहरी मजबूरी या हस्तक्षेप के अभाव को परिभाषित करती है। सामाजिक न्याय समाज की उन संरचनात्मक असमानताओं को सुधारने का प्रयास करता है जो संसाधनों के वितरण में बाधा डालती हैं। ये चारों अवधारणाएं राजनीति विज्ञान के विभिन्न वैचारिक और व्यावहारिक आयामों को स्पष्ट करने हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

166. (B) चर्च की इच्छा को लागू करने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करना।
मध्यकालीन राजनीतिक चिंतन में राज्य को अक्सर 'धर्मनिरपेक्ष हाथ' के रूप में देखा जाता था, जिसका अर्थ था कि राज्य का मुख्य कर्तव्य चर्च के आध्यात्मिक आदेशों और नैतिक नियमों को भौतिक जगत में लागू करना था। इस विचार के अनुसार, राज्य को चर्च का सहायक अंग माना गया जो अधर्म को रोकने और धर्म की रक्षा के लिए अपनी दमनकारी शक्ति का उपयोग करता था। यह दृष्टिकोण लौकिक सत्ता पर आध्यात्मिक सत्ता की श्रेष्ठता को सिद्ध करता था और यह दर्शाता था कि समाज में राज्य का अस्तित्व केवल चर्च के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

167. (B) सटीक डेटा का विश्लेषण करने के लिए शोध विधियों का उपयोग।
व्यवहारवाद की 'बौद्धिक आधारशिलाओं' में से एक "तकनीक" का तात्पर्य उन उन्नत शोध विधियों और सांख्यिकीय उपकरणों के प्रयोग से है जो आँकड़ों को अधिक सटीक और वस्तुनिष्ठ बनाते हैं। व्यवहारवादियों का मानना था कि राजनीति विज्ञान को वर्णनात्मक विवरणों के स्थान पर गणितीय मॉडल, सर्वेक्षण और व्यवस्थित आँकड़ा विश्लेषण की तकनीकों को अपनाना चाहिए। इन उपकरणों के माध्यम से शोधकर्ता मानवीय व्यवहार में नियमितताओं की पहचान कर सकते थे और सिद्धांतों का वैज्ञानिक सत्यापन कर सकते थे। तकनीक पर यह जोर राजनीति विज्ञान को एक विश्वसनीय 'शुद्ध विज्ञान' के रूप में विकसित करने के लिए दिया गया था।

168. (B) स्वयं कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर संशोधनवाद के।
माओ जेदोंग के परिवर्तन के सिद्धांत में सांस्कृतिक क्रांति का उद्देश्य केवल बाहरी शत्रुओं से लड़ना नहीं था, बल्कि स्वयं कम्युनिस्ट पार्टी और सरकारी तंत्र के भीतर पनप रहे 'संशोधनवाद' और नौकरशाही प्रवृत्तियों को जड़ से समाप्त करना था। माओ का मानना था कि क्रांति की समाप्ति के बाद पुराने मूल्य और पूंजीवादी विचार फिर से उभर सकते हैं, जिससे समाजवाद की भावना कमजोर हो जाएगी। अतः उन्होंने युवाओं को लामबंद किया ताकि वे उन नेताओं और अधिकारियों को चुनौती दे सकें जिन्होंने क्रांतिकारी मार्ग को छोड़कर सुविधाभोगी जीवन अपना लिया था।

169. (B) कानून सभी नागरिकों पर निष्पक्ष रूप से लागू होता है।
कानूनी समानता, जिसे "कानून के समक्ष समानता" के रूप में भी जाना जाता है, का मूल अर्थ यह है कि किसी भी नागरिक की सामाजिक स्थिति, जाति, धर्म या धन की परवाह किए बिना कानून सभी पर समान रूप से लागू होना चाहिए। यह उदारवादी न्याय प्रणाली का एक अनिवार्य स्तंभ है जो यह गारंटी देता है कि किसी को भी विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होंगे और प्रत्येक व्यक्ति को समान कानूनी सुरक्षा प्राप्त होगी। यह अवधारणा इस विश्वास पर आधारित है कि न्याय केवल तभी संभव है जब नियम वस्तुनिष्ठ और सर्वव्यापी हों, जिससे समाज में कानून का शासन और निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सके।

NODIA

170. (A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
महात्मा गांधी का परिवर्तन का सिद्धांत राजनीति को नीतिशास्त्र और आध्यात्मिकता से अलग नहीं करता, बल्कि वह इसे पूरी तरह नैतिकता पर आधारित मानता है। गांधीजी के लिए सत्य और अहिंसा केवल राजनीतिक नारे नहीं थे, बल्कि वे शाश्वत नैतिक अनिवार्यताएं थीं जिन्हें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपनाना अनिवार्य था। उनका मानना था कि समाज में कोई भी वास्तविक और स्थायी परिवर्तन तब तक नहीं आ सकता जब तक कि व्यक्ति और समाज के कार्य इन नैतिक मूल्यों द्वारा निर्देशित न हों। अतः गांधीवादी दर्शन में राजनीति आत्म-शुद्धि और सत्य की सेवा का एक माध्यम है।

171. (C) एंग्लो-अमेरिकन दुनिया
"राजनीतिक सिद्धांत के पतन" का शोध प्रबंध मुख्य रूप से बीसवीं शताब्दी के मध्य में एंग्लो-अमेरिकन विश्वविद्यालयों में अनुशासन की स्थिति पर एक तीखी टिप्पणी थी। डेविड ईस्टन और अल्फ्रेड कोब्बन जैसे विचारकों ने महसूस किया कि इस क्षेत्र में नए और रचनात्मक सिद्धांतों का निर्माण रुक गया है और विद्वान केवल अतीत के विचारकों की व्याख्याओं में ही लगे हुए हैं। उनकी यह आलोचना मुख्य रूप से ब्रिटेन और अमेरिका की शैक्षणिक परंपराओं की ओर निर्देशित थी, जिसने बाद में सिद्धांत के पुनरुत्थान के लिए मार्ग प्रशस्त किया।

172. (A) समानता को बढ़ावा देने के लिए कुछ स्वतंत्रताओं को सीमित करने की आवश्यकता हो सकती है।
स्वतंत्रता और समानता के बीच का तनाव राजनीति विज्ञान का एक चिरस्थायी विषय है। कई बार समाज में आर्थिक या सामाजिक समानता स्थापित करने के लिए राज्य को व्यक्तियों की संपत्ति या अनुबंध करने की असीमित स्वतंत्रता पर अंकुश लगाना पड़ता है। उदाहरण के लिए, पुनर्वितरणकारी कर नीतियां आर्थिक समानता तो लाती हैं, लेकिन वे व्यक्ति की अपनी आय को पूर्णतः खर्च करने की नकारात्मक स्वतंत्रता को सीमित कर सकती हैं। इन दोनों मूल्यों के बीच संतुलन बनाना किसी भी न्यायपूर्ण लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए सबसे बड़ी वैचारिक और नीतिगत चुनौती होती है।

173. (C) यह विचारों की विविधता को प्रोत्साहित करती है।
सर्वाधिकारवादी विचारधारा की मुख्य विशेषता यह है कि वह जीवन के प्रत्येक पहलू पर पूर्ण नियंत्रण चाहती है और वह सत्य के अपने 'एकल' दृष्टिकोण के प्रति अटूट निष्ठा की मांग करती है। ऐसी व्यवस्थाओं में विचारों की विविधता या असहमति के लिए कोई स्थान नहीं होता है; इसके विपरीत, ये विचारधाराएँ विरोध को दबाने और पूरे समाज को एक ही सांचे में ढालने का प्रयास करती हैं। सर्वाधिकारवाद अक्सर एक विशिष्ट शत्रु समूह की पहचान करता है जिसे समाज की सभी बुराइयों का कारण बताकर जनता को लामबंद किया जाता है और वैकल्पिक विचारधाराओं को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया जाता है।

174. (A) प्राचीन ग्रीक और रोमन दार्शनिकों को।
न्याय की यह शास्त्रीय परिभाषा कि "प्रत्येक व्यक्ति को उसका हक देना", प्राचीन ग्रीक और रोमन दार्शनिकों, विशेष रूप से प्लेटो और सिसरो की परंपरा से आती है। इसका तात्पर्य है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता, पद और सामाजिक भूमिका के अनुसार उसका उचित स्थान और अधिकार प्राप्त होना चाहिए। यह अवधारणा न्याय को एक नैतिक और कानूनी व्यवस्था के रूप में देखती है जहाँ संतुलन और व्यवस्था बनाए रखना अनिवार्य है। यद्यपि आधुनिक काल में न्याय की परिभाषाएँ व्यापक हुई हैं, परंतु यह प्राचीन सिद्धांत आज भी निष्पक्षता और आनुपातिक न्याय की चर्चाओं का आधार बना हुआ है।

175. (B) एक वर्गविहीन, कम्युनिस्ट समाज का निर्माण।
लेनिन और माओ दोनों ही मार्क्सवादी विचारधारा के अनुयायी थे और उनके संघर्षों का अंतिम लक्ष्य एक वर्गविहीन, शोषण मुक्त कम्युनिस्ट समाज की स्थापना करना था। वे मानते थे कि क्रांति के माध्यम से पूंजीवादी और सामंती व्यवस्था को नष्ट करने के बाद ही ऐसी सामाजिक व्यवस्था संभव है जहाँ उत्पादन के साधनों पर सामूहिक स्वामित्व हो और वर्ग संघर्ष पूरी तरह समाप्त हो जाए। यद्यपि उनकी रणनीतियाँ और क्रांतिकारी आधार (शहरी मजदूर बनाम ग्रामीण किसान) अलग-अलग थे, परंतु उनका वैचारिक गंतव्य एक ही था—मानव मुक्ति और पूर्ण सामाजिक समानता का आदर्श।

176. (B) उत्तर-व्यवहारवाद अनुभवजन्य पद्धतियों के साथ प्रासंगिकता को एकीकृत करता है।
व्यवहारवाद और उत्तर-व्यवहारवाद के बीच का मुख्य अंतर शोध के उद्देश्य और पद्धति में है। व्यवहारवाद केवल वैज्ञानिक पद्धतियों और आँकड़ा संचय पर केंद्रित था, जिसने अक्सर सामाजिक मूल्यों की उपेक्षा की। इसके विपरीत, उत्तर-व्यवहारवाद ने इन अनुभवजन्य पद्धतियों को पूर्णतः त्यागा नहीं, बल्कि उन्हें 'प्रासंगिकता और कार्य' के साथ एकीकृत किया। इसका अर्थ था कि वैज्ञानिक शोध का उपयोग समाज की ज्वलंत समस्याओं को हल करने के लिए किया जाना चाहिए। उत्तर-व्यवहारवाद ने अनुशासन को अधिक मानवीय और उत्तरदायी बनाते हुए तकनीक और मूल्यों के बीच एक संतुलित संश्लेषण प्रस्तुत करने का प्रयास किया।

177. (B) लौकिक शक्ति पर आध्यात्मिक शक्ति की सर्वोच्चता।
मध्यकालीन यूरोप में जब किसी पोप ने किसी राजा या सम्राट को पदच्युत करने का दावा किया, तो वह वास्तव में लौकिक शक्ति पर आध्यात्मिक शक्ति की सर्वोच्चता का चरम प्रदर्शन था। चर्च के समर्थकों का तर्क था कि चूँकि राजा की सत्ता भी ईश्वर से प्राप्त होती है और पोप पृथ्वी पर ईश्वर के प्रतिनिधि हैं, इसलिए पोप को अधर्मी शासकों को दंडित करने का नैतिक अधिकार है। इस दावे ने मध्यकाल में चर्च और राज्य के बीच के संघर्ष को अपने चरम पर पहुँचा दिया, जिससे संप्रभुता और शासन की वैधता के बारे में मौलिक राजनीतिक प्रश्न खड़े हुए।

178. (A) सकारात्मक स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय।
जब कोई सरकार अपने सभी नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं की गारंटी देती है, तो वह वास्तव में सकारात्मक स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय को प्राथमिकता दे रही होती है। शिक्षा और स्वास्थ्य व्यक्ति को इस

NODIA

योग्य बनाते हैं कि वह अपनी क्षमताओं का पूर्ण विकास कर सके और समाज में सक्रिय भागीदारी कर सके, जो सकारात्मक स्वतंत्रता का मूल है। साथ ही, ये सुविधाएँ बिना किसी भेदभाव के सभी को उपलब्ध कराना सामाजिक न्याय का हिस्सा है, जो समाज की संरचनात्मक असमानताओं को दूर कर एक अधिक न्यायपूर्ण वातावरण तैयार करने का प्रयास करता है।

179. (B) स्व-शासन और अपनी इंद्रियों पर शासन।
गांधीवादी दर्शन में 'स्वराज' का अर्थ केवल राजनीतिक स्वतंत्रता या विदेशी शासन का अंत नहीं है, बल्कि इसका एक गहरा आध्यात्मिक और नैतिक आयाम भी है। स्वराज का अर्थ है 'स्व' का शासन, जिसका तात्पर्य अपनी इंद्रियों, इच्छाओं और स्वयं के व्यवहार पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करना है। गांधीजी का मानना था कि जो व्यक्ति स्वयं पर शासन नहीं कर सकता, वह दूसरों पर शासन करने या वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त करने के योग्य नहीं है। अतः स्वराज आत्म-अनुशासन और व्यक्तिगत नैतिकता पर आधारित एक जीवन पद्धति है जो समाज में वास्तविक लोकतंत्र की नींव रखती है।

180. (A) केवल I और III
विचारधारा समाज के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक जुड़ाव के रूप में कार्य करती है, क्योंकि यह साझा विश्वासों और मूल्यों के माध्यम से लोगों को एकजुट करती है। राजनीतिक दल अक्सर विशिष्ट विचारधाराओं के इर्द-गिर्द ही संगठित होते हैं, जो उनकी नीतियों और चुनावी घोषणापत्रों का आधार बनती हैं। हालाँकि, यह कहना गलत है कि विचारधारा हमेशा अतार्किक होती है; कई विचारधाराएँ तर्कसंगत सिद्धांतों और ऐतिहासिक अनुभवों पर आधारित होती हैं। विचारधारा का उद्देश्य समाज की एक सुसंगत व्याख्या प्रदान करना और सामूहिक कार्रवाई के लिए एक ढांचा तैयार करना होता है, जो इसे राजनीति का अनिवार्य अंग बनाता है।

181. (A) नीतिगत बदलावों और राजनीतिक शुद्धिकरण को सही ठहराने के लिए।
माओ जेदोंग का 'अंतर्विरोधों का सिद्धांत' उनके लिए एक शक्तिशाली वैचारिक उपकरण था जिसके माध्यम से उन्होंने पार्टी के भीतर और बाहर अपने विरोधियों को चिह्नित किया और महत्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तनों को लागू किया। माओ ने तर्क दिया कि समाज में अंतर्विरोध निरंतर बने रहते हैं और उन्हें सुलझाने के लिए निरंतर संघर्ष आवश्यक है। इस सिद्धांत का उपयोग उन्होंने 'संशोधनवाद' के विरुद्ध लड़ने और 'सांस्कृतिक क्रांति' जैसे आंदोलनों को सही ठहराने के लिए किया। यह दृष्टिकोण माओ को राजनीतिक शुद्धिकरण करने और समाज को अपने कट्टरपंथी क्रांतिकारी सिद्धांतों के अनुरूप ढालने की वैधता प्रदान करता था।

182. (B) राजनीतिक अधिकार सहमति से प्राप्त होना चाहिए।
लोकतांत्रिक सिद्धांत की सबसे मौलिक धारणा यह है कि किसी भी सरकार या सत्ता का राजनीतिक अधिकार केवल शासितों की सहमति से ही प्राप्त होना चाहिए। यह विचार राजशाही या तानाशाही के पूर्णतः विपरीत है, जहाँ शक्ति बल या वंशानुगत अधिकार पर आधारित होती है। लोकतंत्र में सहमति का अर्थ है कि नागरिक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के माध्यम से अपने शासकों का चुनाव करते हैं और उन्हें शासन करने की वैधता प्रदान करते हैं। यह सिद्धांत इस विश्वास पर आधारित है कि संप्रभुता जनता में निहित है और सरकार केवल उनकी प्रतिनिधि और उनके प्रति जवाबदेह है।

183. (A) राजनीति का अध्ययन तत्काल व्यावहारिक चिंता के बिना किया जाना चाहिए।
व्यवहारवाद के अंतर्गत 'शुद्ध विज्ञान' का लक्ष्य राजनीति का अध्ययन एक वस्तुनिष्ठ और निष्पक्ष वैज्ञानिक दृष्टिकोण से करना था, जिसमें शोधकर्ता किसी भी तात्कालिक राजनीतिक या व्यावहारिक लाभ की चिंता नहीं करता। इसका उद्देश्य राजनीतिक व्यवहार के शाश्वत और सार्वभौमिक नियमों की खोज करना था, जो किसी भी विशिष्ट समय या परिस्थिति से प्रभावित न हों। व्यवहारवादियों का मानना था कि जैसे प्राकृतिक विज्ञान केवल सत्य की खोज के लिए कार्य करते हैं, वैसे ही राजनीति विज्ञान को भी केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए समर्पित होना चाहिए। हालाँकि, बाद में इसी दृष्टिकोण की आलोचना उत्तर-व्यवहारवाद द्वारा की गई।

184. (B) शक्ति के अलग-अलग अधिकार क्षेत्रों को परिभाषित करने।
पोप जेलासियस प्रथम द्वारा प्रस्तुत दो तलवारों के सिद्धांत को मध्यकालीन यूरोप में शक्ति के दो मुख्य अधिकार क्षेत्रों—आध्यात्मिक और लौकिक—के बीच एक स्पष्ट विभाजन और संतुलन बनाने के प्रारंभिक प्रयास के रूप में देखा जा सकता है। इस सिद्धांत ने यह स्थापित करने की कोशिश की कि चर्च और राज्य दोनों की अपनी विशिष्ट भूमिकाएँ और सीमाएँ हैं और उन्हें एक-दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यह वैचारिक ढांचा समाज के सुचारु संचालन के लिए दोनों सत्ताओं के बीच सहयोग और परस्पर सम्मान की भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विकसित किया गया था।

185. (A) औपचारिक न्याय का सिद्धांत।
औपचारिक न्याय का सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि समान मामलों में समान व्यवहार किया जाना चाहिए और नियमों को बिना किसी पक्षपात के सभी पर समान रूप से लागू किया जाना चाहिए। यह कानून के शासन और निष्पक्षता की आधारशिला है। इसका मुख्य बल इस बात पर होता है कि प्रक्रिया में किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी सामाजिक स्थिति या अन्य व्यक्तिगत कारणों से भेदभाव नहीं होना चाहिए। यद्यपि यह सामाजिक या आर्थिक विषमताओं को सीधे हल नहीं करता, परंतु यह कानूनी प्रणाली की विश्वसनीयता और नागरिकों के समान दर्जे को सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है।

186. (B) एक भारी औद्योगिक, शहरीकृत अर्थव्यवस्था।
महात्मा गांधी का नए समाज का दृष्टिकोण भारी औद्योगिकीकरण और बड़े शहरी केंद्रों के पूर्णतः विरुद्ध था, क्योंकि वे इन्हें शोषण और हिंसा का प्रतीक मानते थे। गांधीजी ने एक ऐसे समाज की कल्पना की थी जो आत्मनिर्भर ग्राम गणराज्यों पर आधारित हो और जहाँ अर्थव्यवस्था का केंद्र शारीरिक श्रम और कुटीर उद्योग हों। उनका मानना था कि

Downloaded from www.pdf.tube

वास्तविक स्वतंत्रता विकेंद्रीकरण और सरलता में ही निहित है। बड़े उद्योगों के स्थान पर उन्होंने खादी और ग्रामोद्योग को प्राथमिकता दी ताकि समाज का प्रत्येक व्यक्ति स्वावलंबी बने और मानवीय मूल्यों का ह्रास न हो।

187. (B) अध्ययन की उचित पद्धति और उद्देश्य।
"राजनीतिक सिद्धांत के पतन और पुनरुत्थान" पर हुई ऐतिहासिक बहस मौलिक रूप से इस प्रश्न पर केंद्रित थी कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन की सबसे उचित पद्धति और उसका वास्तविक उद्देश्य क्या होना चाहिए। क्या इसे केवल आँकड़े एकत्र करने और वैज्ञानिक सत्यापन तक सीमित रहना चाहिए, जैसा कि व्यवहारवादियों ने दावा किया, या इसे न्याय, अधिकार और नैतिकता जैसे महान मानकीय मूल्यों की खोज करनी चाहिए? यह बहस अनुशासन की प्रकृति को लेकर थी—क्या यह एक वस्तुनिष्ठ विज्ञान है या एक दार्शनिक और नैतिक चिंतन का विषय है जो समाज को दिशा प्रदान करता है।

188. (A) धन की असमानता को कम करने के लिए विरासत पर उच्च कर।
विरासत पर उच्च कर लगाना स्वतंत्रता और समानता के बीच के तनाव को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। एक तरफ यह नीति समाज में अवसर की समानता बढ़ाने और आर्थिक खाइयों को पाटने का प्रयास करती है, लेकिन दूसरी तरफ यह व्यक्ति की अपनी संपत्ति को अपनी इच्छानुसार हस्तांतरित करने की नकारात्मक स्वतंत्रता को सीमित करती है। यह उदाहरण दिखाता है कि कैसे एक सामाजिक मूल्य (समानता) को प्राप्त करने के लिए दूसरे मूल्य (स्वतंत्रता) के साथ समझौता करना पड़ता है। इन दोनों के बीच संतुलन स्थापित करना आधुनिक लोकतांत्रिक राजनीति की एक निरंतर और जटिल चुनौती बनी हुई है।

189. (C) पश्चिमी क्रांति में देरी की व्याख्या करना।
लेनिन का साम्राज्यवाद का सिद्धांत उनके द्वारा दिया गया एक महत्वपूर्ण सैद्धांतिक योगदान था, जिसके माध्यम से उन्होंने यह स्पष्ट किया कि क्यों विकसित पश्चिमी देशों में मार्क्स की भविष्यवाणी के अनुसार श्रमिक क्रांति नहीं हुई। उन्होंने तर्क दिया कि इन देशों के पूंजीपति वर्ग ने अपने उपनिवेशों से प्राप्त अतिरिक्त लाभ का एक हिस्सा अपने घरेलू श्रमिकों को रियायतें देने में खर्च किया, जिससे उनकी क्रांतिकारी चेतना कम हो गई। इस व्याख्या ने मार्क्सवाद को वैश्विक संदर्भ में विस्तार दिया और औपनिवेशिक शोषण को पूंजीवाद के जीवित रहने के मुख्य कारण के रूप में स्थापित किया।

190. (A) यह महत्वपूर्ण सामाजिक अन्याय के साथ मौजूद रह सकता है।
प्रक्रियात्मक लोकतंत्र की एक प्रमुख आलोचना यह है कि वह केवल चुनावी प्रक्रियाओं और संस्थानों के औपचारिक ढांचे पर ध्यान केंद्रित करता है, जिससे समाज में व्याप्त वास्तविक विषमताओं और अन्यायों की उपेक्षा हो सकती है। ऐसी व्यवस्था में नियमित रूप से निष्पक्ष चुनाव तो हो सकते हैं, लेकिन यदि संपत्ति का वितरण असमान है या कुछ समूहों को दबाया जा रहा है, तो लोकतंत्र का सार नष्ट हो जाता है। आलोचकों का मानना है कि केवल चुनावी प्रक्रिया पर्याप्त नहीं है; जब तक समाज के बुनियादी ढांचे में न्याय और समानता नहीं होगी, तब तक लोकतंत्र केवल एक औपचारिकता बना रहेगा।

191. (D) शास्त्रीय दर्शन के अध्ययन की ओर लौटने की।
लियो स्ट्रॉस और उनके अनुयायियों ने राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद के वैज्ञानिक दृष्टिकोण का कड़ा विरोध किया और शास्त्रीय राजनीतिक दर्शन के गहन अध्ययन की ओर लौटने की वकालत की। उनका मानना था कि सुकरात, प्लेटो और अरस्तू जैसे प्राचीन विचारकों ने राजनीतिक जीवन के सबसे मौलिक और शाश्वत प्रश्नों—जैसे न्याय, सद्गुण और सर्वोत्तम शासन—पर विचार किया था। स्ट्रॉस के अनुसार, आधुनिक सामाजिक विज्ञान ने इन मूल्यों को त्याग दिया है, जिससे समाज नैतिक रूप से दिशाहीन हो गया है। अतः उन्होंने महान दार्शनिक ग्रंथों की सूक्ष्म व्याख्या और दार्शनिक ज्ञान की पुनः स्थापना पर अत्यधिक बल दिया।

NODIA

192. (B) संस्थानों द्वारा उत्पन्न लाभ के प्रतिमानों पर।
सामाजिक न्याय की अवधारणा अनिवार्य रूप से समाज के संस्थानों, कानूनों और आर्थिक व्यवस्थाओं द्वारा उत्पन्न लाभों और बोझों के वितरण के प्रतिमानों पर ध्यान केंद्रित करने की मांग करती है। यह केवल व्यक्तिगत कार्यों की निष्पक्षता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देखती है कि क्या समाज की संरचना सभी के लिए समान अवसर और उचित परिणाम सुनिश्चित कर रही है। सामाजिक न्याय का लक्ष्य उन व्यवस्थागत दोषों को पहचानना और सुधारना है जो कुछ समूहों को स्थायी रूप से लाभ पहुँचाते हैं और दूसरों को पिछड़ा रखते हैं, जिससे एक समग्र न्यायपूर्ण समाज निर्मित हो सके।

193. (D) उपरोक्त सभी।
मध्यकालीन यूरोप में कैथोलिक चर्च केवल एक आध्यात्मिक संस्था नहीं थी, बल्कि वह एक अत्यंत शक्तिशाली लौकिक सत्ता भी थी। चर्च उस समय का सबसे बड़ा भूस्वामी था, जिसके पास विशाल जागीरें थीं। इसके पास अपनी कर प्रणाली थी और वह अक्सर अपनी सुरक्षा और हितों के लिए सैन्य अभियानों को भी प्रभावित करता था। इसके अतिरिक्त, चर्च के पास अपनी अदालतों का एक विस्तृत जाल था, जो समाज के महत्वपूर्ण कानूनी और नैतिक मामलों का निर्णय करता था। इन सभी कारकों ने चर्च को मध्यकालीन राजनीति का एक अनिवार्य और प्रभावी केंद्र बना दिया था।

194. (D) किसान वर्ग की क्रांतिकारी क्षमता पर इसका ध्यान।
माओ जेदोंग का सबसे मौलिक योगदान मार्क्सवाद-लेनिनवाद को चीन की कृषि प्रधान परिस्थितियों के अनुकूल ढालना था। शास्त्रीय मार्क्सवाद के विपरीत, जो औद्योगिक मजदूरों को क्रांति का केंद्र मानता था, माओ ने चीनी ग्रामीण किसानों की क्रांतिकारी क्षमता को पहचाना और उन्हें क्रांति की मुख्य शक्ति बनाया। उन्होंने माना कि एक विशाल और उत्पीड़ित किसान जनसंख्या के बिना चीन में कोई भी क्रांतिकारी परिवर्तन संभव नहीं है। इस दृष्टिकोण ने न केवल चीनी क्रांति को सफल बनाया, बल्कि इसने विकासशील दुनिया के अन्य कृषि प्रधान देशों के लिए भी एक नया क्रांतिकारी मॉडल प्रस्तुत किया।

195. (A) P-4, Q-3, R-1, S-2
लेनिन ने क्रांति को सफल बनाने के लिए एक समर्पित और अनुशासित 'अग्रगामी दल' की भूमिका को अनिवार्य माना। माओ जेदोंग ने ग्रामीण आधार क्षेत्रों के माध्यम से 'किसान-नेतृत्व वाले जनयुद्ध' की रणनीति विकसित की, जिसने चीनी परिस्थितियों में क्रांति को संभव बनाया। महात्मा गांधी का संपूर्ण दर्शन 'सत्याग्रह' और अहिंसक प्रतिरोध के माध्यम से समाज में नैतिक परिवर्तन लाने पर आधारित है। एडमंड बर्क ने क्रांतिकारी उथल-पुथल के स्थान पर संस्थाओं में 'सतर्क और क्रमिक सुधार' की वकालत की ताकि समाज की स्थिरता और परंपराएं बनी रहें। ये चारों विचारक राजनीतिक परिवर्तन के प्रति विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

196. (B) अराजकता से स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कानून आवश्यक है।
यह प्रसिद्ध कथन, जो अक्सर जॉन लॉक के विचारों से जुड़ा है, यह तर्क देता है कि कानून स्वतंत्रता का विरोधी नहीं, बल्कि उसका रक्षक है। बिना नियमों के एक समाज में केवल शक्तिशाली व्यक्ति ही अपनी मनमर्जी कर सकेंगे, जिससे दूसरों की स्वतंत्रता नष्ट हो जाएगी। कानून एक ऐसा ढांचा तैयार करते हैं जो सभी के अधिकारों की रक्षा करता है और व्यक्ति के कार्यों के लिए एक सुरक्षित सीमा निर्धारित करता है। अतः एक न्यायपूर्ण और व्यवस्थित समाज में कानून ही वह माध्यम है जो वास्तविक स्वतंत्रता को संभव और स्थायी बनाता है।

197. (B) वैज्ञानिक जांच को अधिक प्रासंगिक बनाने का आह्वान।
उत्तर-व्यवहारवाद को व्यवहारवाद के विरुद्ध एक प्रति-क्रांति के रूप में नहीं, बल्कि उसे सुधारने और अधिक सार्थक बनाने के आह्वान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसने वैज्ञानिक पद्धतियों को पूरी तरह त्यागने की बात नहीं कही, बल्कि इस पर जोर दिया कि शोध को सामाजिक मूल्यों और समस्याओं के प्रति 'प्रासंगिक' होना चाहिए। उत्तर-व्यवहारवादियों का मानना था कि राजनीति विज्ञान का उद्देश्य केवल ज्ञान के लिए ज्ञान प्राप्त करना नहीं, बल्कि समाज के ज्वलंत संकटों का समाधान खोजना होना चाहिए। इस दृष्टिकोण ने अनुशासन को वैज्ञानिक कठोरता और सामाजिक प्रतिबद्धता के एक नए संतुलन की ओर प्रेरित किया।

198. (C) सामाजिक न्याय
प्रगतिशील आयकर प्रणाली, जहाँ अधिक आय वाले व्यक्तियों पर अधिक कर लगाया जाता है, सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के पूर्णतः अनुरूप है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य आर्थिक संसाधनों का पुनर्वितरण करना है ताकि समाज के वंचित वर्गों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा सकें। यह इस विचार पर आधारित है कि न्याय केवल औपचारिक समानता में नहीं, बल्कि समाज की आर्थिक खाइयों को पाटने और सभी के लिए जीवन की गरिमापूर्ण स्थितियाँ सुनिश्चित करने में निहित है। सामाजिक न्याय के अंतर्गत राज्य का यह हस्तक्षेप एक निष्पक्ष और संतुलित समाज के निर्माण के लिए आवश्यक माना जाता है।

199. (C) जनता का शासन।
लोकतंत्र की अवधारणा का सबसे मौलिक विचार 'जनता का शासन' है, जिसका अर्थ है कि राजनीतिक शक्ति का अंतिम स्रोत संपूर्ण जनता है। यह एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ सरकार का चुनाव नागरिकों द्वारा किया जाता है और वह उनके प्रति जवाबदेह होती है। लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार और अपनी आवाज उठाने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। यद्यपि आधुनिक काल में इसके विभिन्न रूप और प्रक्रियाएं विकसित हुई हैं, परंतु इसका मूल मंत्र सदैव जन-संप्रभुता और जन-कल्याण ही रहा है, जो इसे अन्य सभी शासन प्रणालियों से श्रेष्ठ बनाता है।

200. (A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
मध्यकालीन यूरोप में 'दो तलवारों का सिद्धांत' चर्च और राज्य के बीच निरंतर घर्षण और सत्ता संघर्ष का एक मुख्य कारण बना रहा। यद्यपि इसका उद्देश्य अधिकार क्षेत्रों का विभाजन करना था, परंतु पापल समर्थकों ने आध्यात्मिक श्रेष्ठता के आधार पर लौकिक मामलों में हस्तक्षेप किया, जबकि सम्राटों ने अपनी संप्रभुता को सीधे ईश्वरीय बताकर चर्च के दावों को चुनौती दी। दोनों पक्षों ने इस सिद्धांत की अपने-अपने हितों के अनुसार व्याख्या की ताकि वे अपनी सर्वोच्चता सिद्ध कर सकें। इस वैचारिक द्वंद्व ने मध्ययुगीन राजनीति को अत्यंत जटिल और अस्थिर बना दिया था।

201. (B) राज्य हिंसा का प्रतिनिधित्व करने वाली एक "आत्मारहित मशीन" है।
महात्मा गांधी का राज्य के प्रति दृष्टिकोण अत्यंत आलोचनात्मक था; उन्होंने राज्य को संगठित और संकेंद्रित हिंसा का प्रतीक माना। उनके अनुसार, राज्य एक "आत्मारहित मशीन" है जो व्यक्ति की गरिमा और उसकी नैतिक स्वायत्तता को नष्ट कर देती है, क्योंकि राज्य का आधार अंततः बल प्रयोग होता है। गांधीजी एक ऐसी 'प्रबुद्ध अराजकता' के पक्षधर थे जहाँ व्यक्ति स्वयं पर शासन करे और समाज स्वैच्छिक सहयोग पर आधारित हो। उन्होंने केंद्रीकृत राज्य सत्ता के स्थान पर विकेंद्रीकृत ग्राम गणराज्यों की वकालत की ताकि हिंसा का प्रभाव न्यूनतम हो सके।

202. (A) शोध निष्कर्षों को जहाँ तक संभव हो संख्यात्मक रूप से व्यक्त किया जाना चाहिए।
व्यवहारवाद के अंतर्गत 'परिमाणीकरण' पर जोर देने का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक विश्लेषण को अधिक सटीक, वस्तुनिष्ठ और वैज्ञानिक बनाना था। व्यवहारवादियों का मानना था कि राजनीतिक घटनाओं और व्यवहारों को आँकड़ों के रूप में एकत्र किया जाना चाहिए और सांख्यिकीय पद्धतियों का उपयोग करके उन्हें संख्यात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इससे शोध के निष्कर्षों का सत्यापन संभव हो पाता है और मानवीय पूर्वाग्रहों की संभावना कम हो जाती है। परिमाणीकरण ने राजनीति विज्ञान को पारंपरिक वर्णनात्मक पद्धति से हटाकर एक आँकड़ा-आधारित भविष्योन्मुखी अनुशासन के रूप में विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

Click Here to Buy book on Amazon

203. (A) कानूनी समानता अनुप्रयोग है; अवसर शुरुआती बिंदु है।
कानूनी समानता और अवसर की समानता न्याय के दो अलग-अलग चरणों को दर्शाते हैं। कानूनी समानता यह सुनिश्चित करती है कि कानून सभी पर बिना किसी भेदभाव के समान रुप से 'लागू' हो, जो एक निष्पक्ष न्याय प्रणाली का आधार है। इसके विपरीत, अवसर की समानता समाज के सभी सदस्यों को अपनी प्रतिभा के अनुसार आगे बढ़ने के लिए एक समान 'शुरुआती बिंदु' या मंच प्रदान करने से संबंधित है, ताकि कोई भी सामाजिक बाधाओं के कारण पीछे न रहे। जहाँ कानूनी समानता नियमों की निष्पक्षता सुनिश्चित करती है, वहीं अवसर की समानता वास्तविक प्रतिस्पर्धा को न्यायपूर्ण बनाती है।

204. (D) माओ जेदोंग
"शक्ति बंदूक की नली से निकलती है" यह प्रसिद्ध कथन माओ जेदोंग के क्रांतिकारी दर्शन का सारांश प्रस्तुत करता है। माओ का मानना था कि शोषक वर्गों और साम्राज्यवादी शक्तियों को केवल शांतिपूर्ण वार्ता या चुनावों के माध्यम से नहीं हटाया जा सकता। उनके अनुसार, वास्तविक राजनीतिक परिवर्तन और सर्वहारा की सत्ता की स्थापना के लिए सशस्त्र संघर्ष और सैन्य शक्ति अनिवार्य है। यह विचार क्रांति में हिंसा की भूमिका और जनता की लामबंदी के महत्व को रेखांकित करता है, जिसने चीनी साम्यवादी आंदोलन की रणनीति और सफलता में एक निर्णायक भूमिका निभाई थी।

205. (A) इस विचार की कि प्रश्नों का एक नैतिक आयाम होता है।
राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान ने इस मौलिक विचार को पुनः स्थापित किया कि राजनीतिक जीवन के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों, जैसे न्याय, स्वतंत्रता और दायित्व का एक अनिवार्य नैतिक और दार्शनिक आयाम होता है। व्यवहारवाद ने इन विषयों को 'मूल्य-मुक्त' वैज्ञानिक जांच के नाम पर उपेक्षित कर दिया था। पुनरुत्थान के दौरान विद्वानों ने यह महसूस किया कि केवल आँकड़ों और तथ्यों के माध्यम से समाज के उद्देश्यों को नहीं समझा जा सकता। इस नई सराहना ने राजनीति विज्ञान को फिर से एक ऐसे अनुशासन के रुप में जीवंत बनाया जो मानवीय मूल्यों और आदर्श समाज के निर्माण पर गंभीर चिंतन करता है।

206. (B) सांसारिक या शाही अधिकार।
मध्यकालीन राजनीतिक विमर्श में 'रेग्नम' शब्द राजाओं, सम्राटों और धर्मनिरपेक्ष शासकों के अधिकार क्षेत्र को इंगित करता था। यह 'सांसारिक तलवार' का प्रतीक था, जिसका कार्य समाज में व्यवस्था बनाए रखना, बाहरी शत्रुओं से रक्षा करना और नागरिक प्रशासन चलाना था। यह आध्यात्मिक सत्ता से पृथक माना जाता था, जिसका मुख्य सरोकार आत्माओं का कल्याण था। रेग्नम और आध्यात्मिक सत्ता के बीच के संबंधों की जटिलता और उनके अधिकार क्षेत्र की सीमाओं का विवाद मध्यकालीन राजनीतिक चिंतन और सत्ता संघर्ष का सबसे प्रमुख विषय रहा है।

207. (B) व्यक्तिगत न्याय बनाम सामाजिक न्याय
कम आय वाले क्षेत्र के लिए सार्वजनिक पुस्तकालय और संपन्न क्षेत्र के लिए सड़क मरम्मत के बीच की बहस व्यक्तिगत लाभ और सामूहिक निष्पक्षता के बीच के संघर्ष को दर्शाती है। व्यक्तिगत न्याय के अनुसार, प्रत्येक क्षेत्र के अपने अधिकार हो सकते हैं, लेकिन सामाजिक न्याय यह मांग करता है कि संसाधनों का वितरण समाज की बुनियादी संरचना में मौजूद असमानताओं को दूर करने के लिए किया जाए। यह बहस इस प्रश्न पर केंद्रित है कि क्या संसाधनों को उन लोगों की ओर मोड़ा जाना चाहिए जिन्हें उनकी सबसे अधिक आवश्यकता है ताकि सामाजिक संतुलन और न्याय स्थापित हो सके, जो सामाजिक न्याय का मूल उद्देश्य है।

208. (A) सामाजिक मुद्दों को हल करने के लिए राजनीति विज्ञान का आह्वान।
उत्तर-व्यवहारवाद में "प्रासंगिकता का सिद्धांत" इस मांग को रेखांकित करता है कि राजनीतिक वैज्ञानिकों के शोध का समाज के ज्वलंत और दबावपूर्ण मुद्दों के साथ सीधा संबंध होना चाहिए। आलोचकों का मानना था कि व्यवहारवाद की तकनीक पर अत्यधिक निर्भरता ने विद्वानों को सामाजिक संकटों के प्रति उदासीन बना दिया है। प्रासंगिकता के सिद्धांत ने यह स्पष्ट किया कि ज्ञान तभी सार्थक है जब वह युद्ध, अन्याय और गरीबी जैसी मानवीय समस्याओं को सुलझाने में योगदान दे सके। यह दृष्टिकोण अकादमिक शोध को सामाजिक जिम्मेदारी और नैतिक प्रतिबद्धता के साथ जोड़ने का एक क्रांतिकारी प्रयास था।

209. (C) सामाजिक
विचारधारा का एक महत्वपूर्ण कार्य व्यक्तियों को एक साझा विश्वास तंत्र और पहचान प्रदान करना है, जिसे इसका 'सामाजिक' कार्य कहा जाता है। यह लोगों को एक बड़े समूह या समुदाय का हिस्सा महसूस कराती है, जिससे उनमें एकजुटता और अपनेपन की भावना विकसित होती है। साझा राजनीतिक पहचान के माध्यम से विचारधारा सामाजिक जुड़ाव को मजबूत करती है और लोगों को एक समान उद्देश्य के लिए मिलकर कार्य करने हेतु प्रेरित करती है। यह पहचान न केवल व्यक्तिगत स्तर पर सुरक्षा प्रदान करती है, बल्कि यह राजनीतिक आंदोलनों और दलों के निर्माण एवं उनकी निरंतरता के लिए भी एक अनिवार्य मनोवैज्ञानिक आधार तैयार करती है।

210. (A) केवल I और II
व्यवहारवाद ने राजनीति विज्ञान को भौतिक और जीव विज्ञान जैसे प्राकृतिक विज्ञानों के मॉडल पर पुनर्गठित करने का प्रयास किया, ताकि इसमें वस्तुनिष्ठता और वैज्ञानिकता लाई जा सके। इस दृष्टिकोण की मुख्य विशेषता व्यक्तियों और समूहों के अवलोकनीय और सत्यापन योग्य राजनीतिक व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करना था। व्यवहारवादियों ने मानकीय प्रश्नों और दार्शनिक मूल्यों को वैज्ञानिक जांच के दायरे से बाहर रखा, क्योंकि वे इसे 'व्यक्तिपरक' मानते थे। अतः कथन I और II व्यवहारवादी आंदोलन के मूल लक्ष्यों और पद्धतियों को सही ढंग से स्पष्ट करते हैं, जबकि III इसके पूर्णतः विपरीत है।

211. (D) "सर्वहारा की तानाशाही" स्थापित करना।
लेनिन के क्रांतिकारी सिद्धांत के अनुसार, पूंजीवाद को उखाड़ फेंकने के तुरंत बाद कम्युनिस्ट पार्टी का मुख्य कार्य "सर्वहारा की तानाशाही" को स्थापित और मजबूत करना है। यह एक

NODIA

संक्रमणकालीन अवस्था है जहाँ राज्य शक्ति का उपयोग पुराने शोषक वर्गों के अवशेषों को समाप्त करने और समाजवाद की नींव रखने के लिए किया जाता है। लेनिन का मानना था कि पार्टी को इस प्रक्रिया में सर्वहारा वर्ग के अग्रगामी के रूप में नेतृत्व करना चाहिए ताकि प्रति-क्रांति को रोका जा सके। यह तानाशाही अंततः एक ऐसे वर्गविहीन समाज की ओर ले जाने के लिए अभीष्ट है जहाँ राज्य स्वयं समाप्त हो जाएगा।

212. (A) दंगों को दबाने के लिए सरकार द्वारा सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध लगाना।
दंगों को रोकने के लिए सरकार द्वारा सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध लगाना स्वतंत्रता और व्यवस्था के बीच के क्लासिक तनाव का एक स्पष्ट उदाहरण है। यहाँ नागरिकों की सभा करने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को समाज में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए सीमित किया जाता है। यह परिदृश्य उस जटिल राजनीतिक दुविधा को दर्शाता है जहाँ राज्य को सार्वजनिक सुरक्षा के नाम पर व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं पर अंकुश लगाना पड़ता है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह इन दोनों प्रतिस्पर्धी मूल्यों के बीच कितना न्यायपूर्ण संतुलन स्थापित कर पाती है।

213. (D) रोमन सम्राट में अधिकार के एकीकरण की।
पोप जेलासियस प्रथम का दो तलवारों का सिद्धांत मुख्य रूप से रोमन साम्राज्य के उस प्रभाव की प्रतिक्रिया थी जहाँ सम्राट आध्यात्मिक और लौकिक दोनों शक्तियों को अपने नियंत्रण में रखने का प्रयास करते थे। जेलासियस ने इस प्रवृत्ति को चुनौती देते हुए तर्क दिया कि ईश्वरीय व्यवस्था के अनुसार इन दोनों सत्ताओं का पृथक्करण अनिवार्य है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पवित्र अधिकार और शाही शक्ति के अपने-अपने स्वतंत्र क्षेत्र हैं। यह सिद्धांत मध्यकालीन यूरोप में चर्च की स्वायत्तता की रक्षा करने और सत्ता के पूर्ण केंद्रीकरण को रोकने की दिशा में एक ऐतिहासिक वैचारिक कदम था।

214. (D) सामाजिक परिणाम और वितरण।
सामाजिक न्याय की अवधारणा का मुख्य सरोकार केवल व्यक्तिगत कानूनी अधिकारों तक सीमित नहीं है, बल्कि वह इस बात पर केंद्रित है कि समाज में संसाधनों, अवसरों, धन और मान-सम्मान का वितरण किस प्रकार हो रहा है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि समाज की बुनियादी संरचना न्यायपूर्ण हो और शासन के परिणाम समाज के सभी वर्गों, विशेषकर वंचितों के लिए सकारात्मक हों। सामाजिक न्याय उन व्यापक विषमताओं को दूर करने की मांग करता है जो व्यक्तियों को उनके अधिकारों का पूर्ण उपयोग करने से रोकती हैं। यह एक समावेशी सामाजिक व्यवस्था के निर्माण का संकल्प है।

215. (B) एक प्रमुख अनुशासन शाखा के उद्देश्य को चुनौती दी।
राजनीतिक सिद्धांत के "पतन" का शोध प्रबंध अत्यंत विवादास्पद था क्योंकि इसने राजनीति विज्ञान की सबसे पुरानी और सबसे महत्वपूर्ण शाखा—राजनीतिक दर्शन—के अस्तित्व और प्रासंगिकता पर गंभीर प्रश्न खड़े किए थे। डेविड ईस्टन और अन्य आलोचकों ने यह तर्क देकर हलचल मचा दी थी कि यह अनुशासन अब रचनात्मक नहीं रहा और अपनी दार्शनिक गहराई खो चुका है। इस दावे ने विद्वानों को अपनी शोध पद्धतियों और सिद्धांतों के प्रति पुनर्मूल्यांकन करने के लिए मजबूर किया। इस विवाद ने ही अंततः अनुशासन में एक नए बौद्धिक विमर्श और सिद्धांत के पुनरुत्थान के लिए आवश्यक ऊर्जा और आधार प्रदान किया।

216. (C) सत्य और न्याय के लिए नैतिक संघर्ष करने का।
गांधीजी के लिए 'सत्याग्रह' केवल एक राजनीतिक हथियार नहीं था, बल्कि यह सत्य और न्याय की स्थापना के लिए किया जाने वाला एक गहन नैतिक संघर्ष था। सत्याग्रह का अर्थ है "सत्य के प्रति आग्रह", जो पूर्णतः अहिंसा और आत्मिक बल पर आधारित है। इसका उद्देश्य शत्रु को पराजित करना या उसे अपमानित करना नहीं, बल्कि स्वेच्छा से कष्ट सहकर और सत्य पर अडिग रहकर विरोधी के हृदय को परिवर्तित करना है। गांधीजी का मानना था कि नैतिक साधनों के माध्यम से प्राप्त जीत ही वास्तविक और स्थायी होती है, जो समाज में स्थायी शांति और सामंजस्य लाती है।

217. (C) गांधीवादी सिद्धांत - अग्रगामी दल
'अग्रगामी दल' की अवधारणा लेनिन के क्रांतिकारी सिद्धांत का केंद्र है, न कि गांधीवादी चिंतन का। गांधीजी का दर्शन सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह और विकेंद्रीकरण पर आधारित है, जहाँ वे जनता की स्वतःस्फूर्त भागीदारी और नैतिक उत्थान पर बल देते हैं। इसके विपरीत, लेनिन ने क्रांति के सफल संचालन के लिए पेशेवर और अनुशासित क्रांतिकारियों के एक छोटे समूह के नेतृत्व को अनिवार्य माना। अन्य युग्म सही हैं: व्यवहारवाद मूल्य-मुक्त विश्लेषण से जुड़ा है, उत्तर-व्यवहारवाद प्रासंगिकता से, और मध्यकालीन चिंतन दो तलवारों के सिद्धांत से। अतः गांधी और अग्रगामी दल का युग्म पूरी तरह गलत है।

218. (A) पार्टी को जनता के विचारों को संश्लेषित करना और समझाना चाहिए।
माओ जेदोंग के "जन-लाइन" सिद्धांत का मूल मंत्र है "जनता से लो और जनता को दो"। इसका अर्थ है कि कम्युनिस्ट पार्टी को आम जनता के बिखरे हुए और असंगठित विचारों एवं शिकायतों को एकत्र करना चाहिए, उन्हें मार्क्सवादी-लेनिनवादी सिद्धांतों की रोशनी में व्यवस्थित और स्पष्ट करना चाहिए, और फिर उन्हें व्यापक नीतियों के रूप में वापस जनता के पास ले जाना चाहिए। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि पार्टी का नेतृत्व सदैव जनता की वास्तविक आवश्यकताओं और आकांक्षाओं से जुड़ा रहे, जिससे क्रांति को व्यापक जनसमर्थन और निरंतरता प्राप्त होती रहे।

219. (D) राजनीतिक समानता
'एक व्यक्ति, एक वोट' का सिद्धांत राजनीतिक समानता की सबसे सशक्त अभिव्यक्ति है, जो प्रत्येक नागरिक को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में समान दर्जा प्रदान करता है। यह सिद्धांत इस विश्वास पर आधारित है कि शासन की वैधता के लिए प्रत्येक नागरिक की सहमति और भागीदारी का समान महत्व है, चाहे उसकी आर्थिक या सामाजिक स्थिति कुछ भी

Downloaded from www.pdf.tube

हो। राजनीतिक समानता किसी भी प्रकार के विशेषाधिकार को पूरी तरह अस्वीकार करती है और यह सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक वयस्क नागरिक को शासन के निर्णयों को प्रभावित करने का समान अवसर प्राप्त हो। यह आधुनिक नागरिकता और लोकतांत्रिक संप्रभुता का अनिवार्य आधार है।

220. (A) 1, 3, 2, 4
इन घटनाओं का सही कालानुक्रमिक क्रम राजनीतिक विचारों के ऐतिहासिक विकास को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। सबसे पहले, जेलासियन सिद्धांत (पाँचवीं शताब्दी) ने मध्यकालीन चर्च और राज्य के बीच शक्तियों के विभाजन की नींव रखी। इसके सदियों बाद, 1917 में लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक क्रांति हुई। इसके पश्चात, 1950 के दशक में व्यवहारवाद का उदय हुआ, जिसने राजनीति विज्ञान को वैज्ञानिक बनाने का प्रयास किया। अंत में, 1971 में जॉन रॉल्स की "न्याय का सिद्धांत" प्रकाशित हुई, जिसने राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान में निर्णायक भूमिका निभाई। यह क्रम अनुशासन के प्राचीन से आधुनिक चरणों को दर्शाता है।

221. (A) यह घटनाओं की धारणा और व्याख्या को आकार देती है।
विचारधारा को एक 'लेंस' के रूप में देखने का अर्थ है कि यह हमारे सामने आने वाली राजनीतिक और सामाजिक घटनाओं को देखने, समझने और उनकी व्याख्या करने के तरीके को गहराई से प्रभावित करती है। जैसे एक विशिष्ट रंग का लेंस दुनिया को उसी रंग में दिखाता है, वैसे ही एक विचारधारा हमें यह बताती है कि समाज के कौन से मुद्दे महत्वपूर्ण हैं और उन्हें किस दृष्टिकोण से सुलझाया जाना चाहिए। यह व्यक्तियों के पूर्वाग्रहों, अपेक्षाओं और निर्णयों को एक सुसंगत ढांचा प्रदान करती है, जिससे वे राजनीतिक वास्तविकता को अपनी विश्वदृष्टि के अनुरूप ढाल सकें और उसमें सक्रिय भूमिका निभा सकें।

222. (C) 'बड़े प्रश्नों' पर फिर से रचनात्मक रूप से बहस की जा रही थी।
"राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान" के समर्थकों ने यह तर्क दिया कि व्यवहारवाद के दौर में उपेक्षित किए गए न्याय, स्वतंत्रता, अधिकार और नैतिकता जैसे 'बड़े मानकीय प्रश्नों' पर विद्वान फिर से रचनात्मक और गहराई से विचार करने लगे हैं। उन्होंने माना कि राजनीति का अध्ययन केवल वैज्ञानिक आँकड़ों और सांख्यिकी तक सीमित नहीं रह सकता। जॉन रॉल्स जैसे विचारकों के कार्यों ने यह सिद्ध किया कि दार्शनिक चिंतन अभी भी जीवंत है और समाज को दिशा देने के लिए अनिवार्य है। इस पुनरुत्थान ने राजनीतिक चिंतन को फिर से बौद्धिक विमर्श के केंद्र में स्थापित किया।

223. (A) नकारात्मक 'से स्वतंत्रता' है; सकारात्मक 'की स्वतंत्रता' है।
नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता के बीच का अंतर हस्तक्षेप और क्षमता के बीच का अंतर है। नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है 'से स्वतंत्रता', जो व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंधों और बाधाओं के अभाव पर बल देती है ताकि वह अपने निजी क्षेत्र में स्वतंत्र रहे। इसके विपरीत, सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है 'की स्वतंत्रता', जो व्यक्ति की उन क्षमताओं और परिस्थितियों के विकास से संबंधित है जो उसे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और अपना पूर्ण विकास करने में सक्षम बनाती हैं। यशायाह बर्लिन द्वारा स्पष्ट किया गया यह अंतर स्वतंत्रता के व्यक्तिवादी और सामाजिक आयामों को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

224. (A) पोप और चर्च पदानुक्रम
मध्यकालीन राजनीतिक चिंतन और दो तलवारों के सिद्धांत के अंतर्गत 'आध्यात्मिक तलवार' का अधिकार पूर्णतः पोप और चर्च के पदानुक्रम में निहित माना गया था। इस तलवार का मुख्य कार्य मानव आत्माओं का मार्गदर्शन करना, धार्मिक सिद्धांतों की रक्षा करना और समाज के नैतिक आचरण को सुनिश्चित करना था। चर्च ने यह तर्क दिया कि आत्मा का उद्धार सांसारिक जीवन से अधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए आध्यात्मिक तलवार का मूल्य लौकिक तलवार से श्रेष्ठ है। यह अवधारणा मध्यकाल में चर्च को राजाओं और सम्राटों के ऊपर एक उच्च नैतिक और राजनीतिक दर्जा प्रदान करने का मुख्य आधार थी।

NODIA

225. (D) पिछले भेदभाव के लिए सामाजिक न्याय
विश्वविद्यालय प्रवेश जैसी प्रक्रियाओं में सकारात्मक कार्रवाई की नीतियां सामाजिक न्याय के उस सिद्धांत का व्यावहारिक अनुप्रयोग हैं जो ऐतिहासिक भेदभाव और पिछड़ेपन को दूर करने का प्रयास करता है। ये नीतियां यह स्वीकार करती हैं कि समाज के कुछ समूहों को सदियों से अवसरों से वंचित रखा गया है, इसलिए केवल वर्तमान में समान नियम बनाना पर्याप्त नहीं है। उन्हें मुख्यधारा में लाने के लिए विशेष सहायता या आरक्षण देना अनिवार्य है ताकि वास्तविक समानता स्थापित हो सके। यह वितरणात्मक न्याय का एक रूप है जो समाज के विभिन्न वर्गों के बीच संतुलन और निष्पक्षता लाने का लक्ष्य रखता है।

226. (D) पूंजीवादी श्रृंखला की "सबसे कमजोर कड़ी" था।
लेनिन ने मार्क्स के इस विचार को चुनौती दी कि क्रांति केवल उन्नत पूंजीवादी देशों में ही होगी। उन्होंने तर्क दिया कि वैश्विक साम्राज्यवाद के युग में, क्रांति उस देश में होने की सबसे अधिक संभावना है जो पूंजीवादी श्रृंखला की "सबसे कमजोर कड़ी" है, जहाँ आंतरिक और बाहरी अंतर्विरोध सबसे तीव्र हैं। रूस उनके लिए इसी कमजोर कड़ी का उदाहरण था, जहाँ एक विकसित सर्वहारा वर्ग की अनुपस्थिति के बावजूद क्रांतिकारी स्थितियाँ परिपक्व थीं। इस सिद्धांत ने पिछड़े और औपनिवेशिक देशों में भी साम्यवादी क्रांति की संभावना को सैद्धांतिक रूप से पुष्ट किया और वैश्विक राजनीति की दिशा बदल दी।

227. (B) "जानना कार्य करने की जिम्मेदारी लेना है।"
उत्तर-व्यवहारवादी स्थिति का सबसे सटीक सारांश यह है कि ज्ञान और कार्य को एक-दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। उत्तर-व्यवहारवादियों ने तर्क दिया कि यदि कोई विद्वान समाज की बुराइयों और संकटों के बारे में जानता है, तो उसकी यह नैतिक जिम्मेदारी है कि वह उस ज्ञान का उपयोग समाज को सुधारने के लिए करें। केवल तटस्थ होकर आँकड़ा संचय करना बौद्धिक विलासिता है; वास्तविक विज्ञान को मानवीय कल्याण के लिए सक्रिय होना चाहिए। यह विचार राजनीति

विज्ञान को केवल एक शैक्षणिक विषय के बजाय सामाजिक परिवर्तन के एक प्रभावी माध्यम के रूप में पुनर्परिभाषित करता है।

228. (B) निर्णय लेने की प्रक्रियाओं का एक समूह।
लोकतंत्र की अवधारणा मुख्य रूप से उन विधियों और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं के प्रति प्रतिबद्धता दर्शाती है जो जनभागीदारी और सहमति पर आधारित होती हैं। इसमें चुनाव, विचार-विमर्श, बहुमत का शासन और अल्पसंख्यकों के अधिकारों का सम्मान जैसी प्रक्रियाएं शामिल हैं। यद्यपि लोकतंत्र के अलग-अलग आर्थिक या सामाजिक लक्ष्य हो सकते हैं, परंतु इसका मूल स्वरूप इस बात से निर्धारित होता है कि सत्ता का प्रयोग किस प्रकार किया जा रहा है और क्या नागरिक उन निर्णयों को प्रभावित करने की शक्ति रखते हैं जो उनके जीवन को प्रभावित करते हैं। यह पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करता है।

229. (D) इतिहास के प्राथमिक चालक के रूप में वर्ग संघर्ष
वर्ग संघर्ष को इतिहास का प्राथमिक चालक मानना मार्क्सवादी विचारधारा का मूल तत्व है, न कि गांधीवादी चिंतन का। महात्मा गांधी ने समाज के विश्लेषण के लिए वर्ग संघर्ष के स्थान पर मानवता की एकता, हृदय परिवर्तन और नैतिक संघर्ष पर बल दिया। उनके अनुसार, समाज का कल्याण सभी वर्गों के बीच सहयोग और प्रेम से संभव है, न कि उनके बीच हिंसक संघर्ष से। स्वराज और अहिंसा उनके दर्शन के अन्य अनिवार्य अंग हैं। गांधीजी का मानना था कि वर्ग भेद को 'न्यासधारिता' के माध्यम से शांतिपूर्ण ढंग से हल किया जा सकता है, जो उन्हें मार्क्सवादी विचारों से अलग करता है।

230. (C) इतिहासवाद
राजनीतिक सिद्धांत के "पतन" के शोध प्रबंध ने यह तर्क दिया कि बीसवीं शताब्दी में सिद्धांत का ह्रास मुख्य रूप से व्यवहारवाद की वैज्ञानिक शुष्कता और इतिहासवाद के प्रभाव के कारण हुआ था। इतिहासवाद ने सिद्धांतों को उनके विशिष्ट काल और परिस्थितियों तक सीमित कर दिया, जिससे उनके शाश्वत और सार्वभौमिक मूल्यों की उपेक्षा हुई। इसके कारण राजनीतिक चिंतन केवल ऐतिहासिक तथ्यों के विवरण तक सिमट कर रह गया और भविष्य के लिए नए दार्शनिक एवं मानकीय आधार विकसित करने की क्षमता खो दी। इन प्रवृत्तियों ने राजनीतिक सिद्धांत को उसकी रचनात्मकता और शक्ति से वंचित कर दिया था।

231. (C) सामाजिक प्रतिस्पर्धा के लिए एक "समान अवसर का मैदान"।
अवसर की समानता के पीछे मूल विचार समाज के सभी सदस्यों के लिए एक ऐसी व्यवस्था बनाना है जहाँ प्रत्येक व्यक्ति को अपनी प्रतिभा और कड़ी मेहनत के आधार पर सफल होने की समान संभावना प्राप्त हो। इसका उद्देश्य जन्म, जाति या आर्थिक पृष्ठभूमि जैसी कृत्रिम बाधाओं को हटाना है ताकि किसी भी व्यक्ति की प्रगति केवल उसके अपने प्रयासों पर निर्भर करे। यह एक 'समान अवसर का मैदान' तैयार करने जैसा है, जहाँ दौड़ शुरु होने से पहले सभी प्रतियोगी एक ही रेखा पर खड़े हों। यह अवधारणा प्रतिस्पर्धा की निष्पक्षता और व्यक्तिगत योग्यता के सम्मान पर आधारित है।

232. (B) ईश्वर से
मध्यकालीन राजनीतिक चिंतन में सत्ता और अधिकार के लिए अंतिम औचित्य पूर्णतः ईश्वरीय इच्छा में निहित माना जाता था। यह माना जाता था कि राजाओं का शासन करने का अधिकार और पोप की आध्यात्मिक सत्ता दोनों ही ईश्वर द्वारा प्रदत्त हैं। 'राजाओं का दैवीय अधिकार' और 'दो तलवारों का सिद्धांत' इसी विश्वास पर आधारित थे। इस काल में संप्रभुता का अर्थ जनता की सहमति के बजाय ईश्वरीय आदेशों का पालन करना था। राजनीतिक चिंतन का मुख्य उद्देश्य यह समझना था कि मानवीय कानून ईश्वरीय और प्राकृतिक कानूनों के साथ किस प्रकार सामंजस्य बिठा सकते हैं।

233. (A) विश्वासों को प्राकृतिक और निर्विवाद रूप में प्रस्तुत करना।
विचारधारा का एक मुख्य कार्य अपने विशिष्ट विश्वासों, मूल्यों और लक्ष्यों को इस प्रकार प्रस्तुत करना है कि वे समाज को पूरी तरह से 'प्राकृतिक' और 'निर्विवाद' लगें। यह लोगों की चेतना को इस तरह प्रभावित करती है कि वे मौजूदा व्यवस्था या प्रस्तावित परिवर्तनों को एकमात्र सत्य के रूप में स्वीकार कर लेते हैं और उन पर प्रश्न उठाना बंद कर देते हैं। इस प्रकार विचारधारा शक्ति संरचनाओं को स्थायित्व प्रदान करती है और उन्हें जन-स्वीकृति दिलाने में मदद करती है। यह केवल सूचना प्रदान नहीं करती, बल्कि वास्तविकता की एक ऐसी व्याख्या निर्मित करती है जो लोगों के कार्यों का मार्गदर्शन करती है।

234. (D) किसान वर्ग को मुख्य शक्ति के रूप में पहचानता है।
माओ जेदोंग का सिद्धांत शास्त्रीय मार्क्सवाद-लेनिनवाद से इसलिए भिन्न है क्योंकि इसने चीन की विशिष्ट परिस्थितियों को देखते हुए ग्रामीण किसान वर्ग को क्रांति की मुख्य शक्ति के रूप में पहचाना। जहाँ मार्क्स और लेनिन ने शहरी औद्योगिक मजदूरों के नेतृत्व पर बल दिया था, वहीं माओ ने तर्क दिया कि एक कृषि प्रधान देश में किसानों के बिना कोई भी सफल क्रांति असंभव है। उन्होंने किसानों को राजनीतिक रूप से लामबंद किया और "गांवों द्वारा शहरों को घेरने" की एक नई क्रांतिकारी रणनीति विकसित की, जिसने मार्क्सवादी चिंतन को एक नया आयाम और भौगोलिक विस्तार प्रदान किया।

235. (A) उदारवाद
व्यक्तिगत न्याय की अवधारणा उदारवाद की विचारधारा से अत्यंत गहराई से जुड़ी हुई है, जो व्यक्ति की स्वायत्तता, उसके मौलिक अधिकारों और कानून के शासन को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। उदारवादी चिंतन के अनुसार, न्याय का अर्थ प्रत्येक व्यक्ति के साथ निष्पक्ष और समान व्यवहार सुनिश्चित करना है, जिसमें उसकी स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा की गारंटी हो। यह दृष्टिकोण समाज के सामूहिक हितों के ऊपर व्यक्ति के कानूनी और नैतिक अधिकारों को रखता है। उदारवाद में न्यायपालिका की भूमिका व्यक्तियों के अधिकारों के रक्षक के रूप में होती है, जो यह सुनिश्चित करती है कि राज्य मनमाना हस्तक्षेप न करे।

Click Here to Buy book on Amazon

236. (B) मूल्य-मुक्त दृष्टिकोण की सीमाओं की मान्यता।
डेविड ईस्टन का व्यवहारवाद के प्रमुख प्रणेता होने के बाद उत्तर-व्यवहारवाद की ओर मुड़ना इस बात की महत्वपूर्ण मान्यता थी कि राजनीति विज्ञान में केवल 'मूल्य-मुक्त' वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर्याप्त नहीं है। उन्होंने स्वीकार किया कि तकनीक और आँकड़ों पर अत्यधिक बल देने से अनुशासन सामाजिक सरोकारों और मानवीय मूल्यों से दूर हो गया है। ईस्टन का यह वैचारिक परिवर्तन यह दर्शाता है कि वैज्ञानिक कठोरता के साथ-साथ शोध की प्रासंगिकता और सामाजिक प्रतिबद्धता भी अनिवार्य है। इस बदलाव ने राजनीति विज्ञान को एक अधिक संतुलित दिशा प्रदान की, जहाँ वैज्ञानिक पद्धति और मानवीय मूल्यों का समन्वय संभव हो सका।

237. (D) सुरक्षा उपायों के साथ एक प्रतिनिधि प्रणाली।
गणतंत्र की आधुनिक समझ एक ऐसी प्रतिनिधि शासन प्रणाली के रूप में है जहाँ राज्य का प्रमुख वंशानुगत नहीं होता, बल्कि जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। गणतंत्र में केवल बहुमत का शासन नहीं होता, बल्कि इसमें संवैधानिक सुरक्षा उपाय और संस्थागत नियंत्रण भी होते हैं ताकि बहुमत की शक्ति निरंकुश न हो सके और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की जा सके। यह कानून के शासन और जन-संप्रभुता पर आधारित एक व्यवस्थित ढांचा है जो सरकार को नागरिकों के प्रति जवाबदेह बनाता है और सत्ता के दुरुपयोग को रोकने का प्रयास करता है।

238. (C) परिणाम की समानता
"प्रत्येक से उसकी क्षमता के अनुसार, प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार" यह प्रसिद्ध मार्क्सवादी नारा परिणाम की समानता की अवधारणा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। यह सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि एक न्यायपूर्ण समाज में संसाधनों का वितरण व्यक्ति के योगदान के बजाय उसकी वास्तविक जरूरतों के आधार पर होना चाहिए। इसका उद्देश्य समाज में मौजूद आर्थिक और भौतिक विषमताओं को पूरी तरह समाप्त करना है ताकि प्रत्येक व्यक्ति एक सम्मानजनक जीवन जी सके। यह केवल समान अवसर देने से संतुष्ट नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की वकालत करता है जहाँ अभाव पूरी तरह खत्म हो जाए।

239. (C) पेशेवर क्रांतिकारियों की एक पार्टी।
लेनिन की प्रसिद्ध कृति "क्या किया जाना चाहिए?" का केंद्रीय विषय एक ऐसी पार्टी की अनिवार्य आवश्यकता है जो समर्पित और पेशेवर क्रांतिकारियों से बनी हो। लेनिन का तर्क था कि श्रमिक वर्ग स्वयं केवल आर्थिक मांगों तक ही सीमित रह सकता है, इसलिए उन्हें राजनीतिक रूप से जागरूक करने और क्रांति का नेतृत्व करने के लिए एक उच्च संगठित और अनुशासित अग्रगामी दल चाहिए। यह पार्टी सर्वहारा वर्ग के मस्तिष्क के रूप में कार्य करेगी, जो क्रांतिकारी सिद्धांतों की रक्षा करेगी और राज्य सत्ता पर कब्जा करने के लिए संघर्ष का कुशल संचालन करेगी। यह संगठनात्मक सिद्धांत लेनिनवाद की सबसे प्रमुख पहचान है।

240. (B) P-4, Q-1, R-2, S-3
सामाजिक न्याय का एक व्यावहारिक रूप सकारात्मक कार्रवाई की नीतियों में देखा जा सकता है जो ऐतिहासिक असमानताओं को सुधारती हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता का उद्देश्य व्यक्ति के जीवन से बाहरी बाधाओं को हटाना है ताकि उसकी स्वायत्तता सुरक्षित रहे। प्रक्रियात्मक लोकतंत्र मुख्य रूप से उन नियमों और संस्थानों पर केंद्रित होता है जो स्वतंत्र और निष्पक्ष बहुदलीय चुनाव सुनिश्चित करते हैं। गांधीवादी सत्याग्रह का सबसे ऐतिहासिक उदाहरण दांडी यात्रा है, जिसने अहिंसक प्रतिरोध की शक्ति को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित किया। ये उदाहरण इन राजनीतिक अवधारणाओं के व्यावहारिक और ऐतिहासिक आयामों को पूरी तरह स्पष्ट करते हैं।

241. (B) दो तलवारों का सिद्धांत
मध्यकालीन यूरोप में राजाओं और पोप के बीच होने वाला पदनियुक्ति विवाद वास्तव में दो तलवारों के सिद्धांत में निहित अंतर्विरोधों की ही एक उग्र अभिव्यक्ति थी। यह संघर्ष इस मौलिक प्रश्न पर था कि बिशपों की नियुक्ति का अधिकार किसके पास होना चाहिए। इस विवाद ने यह स्पष्ट कर दिया कि आध्यात्मिक और लौकिक सत्ताओं के कार्यक्षेत्र इतने गहराई से जुड़े हुए थे कि उनके बीच एक स्पष्ट और स्थायी विभाजन करना व्यावहारिक रूप से अत्यंत कठिन था। यह संघर्ष संप्रभुता और अधिकार क्षेत्र की मध्यकालीन समझ को परिभाषित करने वाला एक महत्वपूर्ण मोड़ सिद्ध हुआ।

242. (C) आपस में जुड़े हुए और गैर-तटस्थ।
उत्तर-व्यवहारवाद यह प्रबल तर्क देता है कि राजनीतिक विश्लेषण में तथ्य और मूल्य कभी भी पूरी तरह अलग नहीं हो सकते; वे अनिवार्य रूप से आपस में जुड़े हुए और पक्षपाती होते हैं। उत्तर-व्यवहारवादियों के अनुसार, शोधकर्ता द्वारा तथ्यों का चयन स्वयं उसके मूल्यों और सामाजिक दृष्टिकोण से प्रभावित होता है। उन्होंने व्यवहारवाद के उस दावे को खारिज कर दिया कि शोध पूरी तरह 'मूल्य-मुक्त' हो सकता है। इसके बजाय, उन्होंने यह माना कि मूल्यों के प्रति जागरूकता और उनकी सामाजिक प्रासंगिकता ही राजनीतिक विज्ञान को एक अर्थपूर्ण और जिम्मेदार अनुशासन बना सकती है जो वास्तविक दुनिया की चुनौतियों का सामना कर सके।

243. (B) न्याय जैसे महान मानकीय विषय।
राजनीतिक सिद्धांत का "पुनरुत्थान" मुख्य रूप से न्याय, स्वतंत्रता, समानता और अधिकारों जैसे महान मानकीय और दार्शनिक विषयों की ओर लौटने और उन पर गहन चर्चा करने से जुड़ा है। व्यवहारवाद के दौर में इन विषयों को 'अवैज्ञानिक' मानकर उपेक्षित कर दिया गया था, परंतु जॉन रॉल्स और अन्य विचारकों के कार्यों ने इन्हें पुनः बौद्धिक विमर्श के केंद्र में स्थापित किया। इस प्रवृत्ति ने यह सिद्ध किया कि राजनीति को समझने के लिए केवल आँकड़े पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि समाज के नैतिक आधारों और उसके उद्देश्यों पर विचार करना अनिवार्य है। इस पुनरुत्थान ने राजनीतिक चिंतन को फिर से उसकी शास्त्रीय गहराई प्रदान की।

Downloaded from www.pdf.tube

244. (B) हिंसा की आवश्यकता और नैतिकता
लेनिन और गांधी के बीच सबसे मौलिक और गहरा अंतर हिंसा की आवश्यकता और उसके नैतिक औचित्य के प्रति उनके दृष्टिकोण में निहित है। लेनिन ने मार्क्सवादी क्रांति को सफल बनाने के लिए सशस्त्र विद्रोह और राज्य सत्ता पर बलपूर्वक कब्जे को एक अनिवार्य और जायज माध्यम माना। इसके विपरीत, गांधीजी ने पूर्णतः अहिंसा और सत्य को साध्य और साधन दोनों के रूप में स्वीकार किया। उनका मानना था कि अनैतिक साधनों से कभी भी एक नैतिक और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण नहीं किया जा सकता। यह वैचारिक मतभेद उनके संघर्ष की पूरी पद्धति, नेतृत्व के स्वरूप और क्रांतिकारी लक्ष्यों को गहराई से प्रभावित करता है।

245. (C) नकारात्मक स्वतंत्रता
मनमानी गिरफ्तारी और राज्य के हस्तक्षेप से मुक्त होने का व्यक्ति का अधिकार नकारात्मक स्वतंत्रता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। नकारात्मक स्वतंत्रता व्यक्ति के चारों ओर एक ऐसे 'सुरक्षित क्षेत्र' की मांग करती है जहाँ राज्य या कोई अन्य बाहरी शक्ति उसकी स्वायत्तता का उल्लंघन न कर सके। यह अवधारणा प्रतिबंधों के अभाव और व्यक्ति की निजी सुरक्षा पर बल देती है ताकि वह दूसरों को नुकसान पहुँचाए बिना अपनी इच्छानुसार कार्य कर सके। यह आधुनिक लोकतांत्रिक और कानूनी प्रणालियों का एक अनिवार्य अंग है जो नागरिकों को राज्य की निरंकुशता से सुरक्षा प्रदान करता है और व्यक्तिगत गरिमा को अक्षुण्ण बनाए रखता है।

246. (B) वांछित समाज प्राप्त करने के लिए चरणों की रूपरेखा तैयार करना।
विचारधारा का 'कार्य के कार्यक्रम' वाला भाग अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह न केवल वर्तमान समाज की बुराइयों को चिह्नित करता है, बल्कि एक आदर्श भविष्य के समाज को प्राप्त करने के लिए विशिष्ट चरणों और रणनीतियों की रूपरेखा भी प्रस्तुत करता है। यह अनुयायियों को यह बताता है कि उन्हें क्या करना है, कैसे संगठित होना है और किन लक्ष्यों के लिए संघर्ष करना है। यह व्यावहारिक दिशा-निर्देश विचारधारा को केवल एक दार्शनिक विचार से ऊपर उठाकर उसे एक शक्तिशाली राजनीतिक उपकरण और लामबंदी के माध्यम के रूप में पुनर्परिभाषित करता है जो समाज को बदलने की क्षमता रखता है।

247. (B) सामाजिक न्याय
'वितरणात्मक न्याय' की अवधारणा सामाजिक न्याय का एक प्रमुख घटक है, जो समाज के सदस्यों के बीच संसाधनों, धन, अवसरों और मान-सम्मान के उचित वितरण पर केंद्रित है। यह सिद्धांत यह मानता है कि न्याय केवल तभी संभव है जब समाज के संस्थानों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि लाभों और बोझों का बंटवारा तर्कसंगत और निष्पक्ष हो। यह केवल व्यक्तिगत योग्यता की बात नहीं करता, बल्कि समाज के वंचित और पिछड़े वर्गों के हितों की रक्षा करने और आर्थिक खाइयों को पाटने की वकालत भी करता है। वितरणात्मक न्याय ही सामाजिक न्याय को उसका वास्तविक स्वरूप प्रदान करता है।

248. (B) विशिष्ट राष्ट्रीय स्थितियों के अनुसार विचारधारा को ढालना।
माओ जेदोंग द्वारा मार्क्सवाद-लेनिनवाद का चीनी परिस्थितियों के अनुकूल किया गया रूपांतरण इस बात का एक उत्कृष्ट उदाहरण है कि कैसे एक वैश्विक विचारधारा को विशिष्ट राष्ट्रीय और सांस्कृतिक संदर्भों के अनुसार ढाला जा सकता है। माओ ने मार्क्स के शहरी सर्वहारा के नेतृत्व वाले सिद्धांत को चीन के ग्रामीण और कृषि प्रधान समाज के अनुरूप बदला और किसानों को क्रांति का मुख्य आधार बनाया। यह वैचारिक लचीलापन और अनुकूलन ही था जिसने चीन में साम्यवादी क्रांति की सफलता सुनिश्चित की। यह दर्शाता है कि विचारधाराएं जड़ सिद्धांत नहीं हैं, बल्कि वे जीवित और गतिशील विचार हैं जो स्थानीय वास्तविकताओं के साथ मिलकर प्रभावी बनती हैं।

249. (A) एक राज्य में सारवान लोकतंत्र के बिना प्रक्रियात्मक लोकतंत्र हो सकता है।
प्रक्रियात्मक और सारवान लोकतंत्र के बीच का संबंध यह स्पष्ट करता है कि केवल चुनावी प्रक्रियाओं का होना वास्तविक लोकतंत्र की गारंटी नहीं है। कई देशों में नियमित रूप से चुनाव होते हैं और बहुदलीय व्यवस्था भी मौजूद होती है, लेकिन वहाँ सामाजिक असमानता, मानवाधिकारों का उल्लंघन और न्याय का अभाव बना रहता है, जो सारवान लोकतंत्र की कमी को दर्शाता है। सारवान लोकतंत्र तभी संभव है जब चुनावी प्रक्रिया के साथ-साथ शासन के परिणाम भी न्यायपूर्ण, समावेशी और लोगों के अधिकारों की रक्षा करने वाले हों। अतः प्रक्रियात्मक ढांचा केवल एक माध्यम है, जबकि सारवान न्याय ही लोकतंत्र का वास्तविक लक्ष्य है।

250. (A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
माओ जेदोंग के क्रांतिकारी सिद्धांत में किसानों को अग्रणी भूमिका प्रदान करना चीन की सामाजिक वास्तविकता की उनकी गहरी समझ का परिणाम था। उन्होंने देखा कि चीन में किसान वर्ग न केवल सबसे अधिक संख्या में था, बल्कि वह साम्राज्यवादी और सामंती शोषण से सबसे अधिक पीड़ित भी था। माओ का मानना था कि शहरी मजदूरों की तुलना में किसानों में विद्रोह की तीव्र भावना और क्रांति की असीम क्षमता मौजूद है। इसलिए उन्होंने किसानों को संगठित किया और उन्हें क्रांति का मुख्य इंजन बनाया, जिससे मार्क्सवादी-लेनिनवादी क्रांति को एक नया ग्रामीण आधार प्राप्त हुआ जो चीनी परिस्थितियों के लिए अनिवार्य था।

251. (C) सिद्धांत और शोध के बीच संबंध।
व्यवहारवाद की एक प्रमुख विशेषता 'व्यवस्थित' होने पर बल देना था, जिसका अर्थ है कि वैज्ञानिक शोध और सिद्धांत निर्माण के बीच एक गहरा संबंध होना चाहिए। व्यवहारवादियों का मानना था कि केवल यादृच्छिक रूप से आँकड़े एकत्र करना पर्याप्त नहीं है; शोध को एक सैद्धांतिक ढांचे के भीतर संचालित होना चाहिए ताकि प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर विश्वसनीय सिद्धांतों का निर्माण किया जा सके। यह व्यवस्थित दृष्टिकोण राजनीति विज्ञान को एक व्यवस्थित अनुशासन बनाने के लिए

NODIA

अनिवार्य माना गया, जहाँ प्रत्येक शोध कार्य ज्ञान की व्यापक संरचना में योगदान देता है और सिद्धांतों के निरंतर सत्यापन एवं परिष्करण में सहायक होता है।

252. (B) केंद्रीकृत राजतंत्र और संप्रभु राज्य
मध्यकालीन यूरोप का एकीकृत ईसाई समाज का आदर्श, जहाँ धर्म और राजनीति एक रूप में जुड़े हुए थे, केंद्रीकृत राजतंत्रों और आधुनिक संप्रभु राज्यों के उदय के साथ धीरे-धीरे समाप्त हो गया। पुनर्जागरण और धर्मसुधार आंदोलनों ने चर्च के सार्वभौमिक अधिकार को चुनौती दी, जिससे शासकों ने अपनी स्वतंत्र राजनीतिक संप्रभुता का दावा करना शुरू किया। राष्ट्र-राज्य की इस नई अवधारणा ने धर्म को व्यक्ति का निजी मामला बनाने और राज्य को एक स्वतंत्र धर्मनिरपेक्ष सत्ता के रूप में स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त किया। इस ऐतिहासिक परिवर्तन ने मध्ययुगीन एकीकृत समाज के स्थान पर आधुनिक विभाजित और संप्रभु वैश्विक व्यवस्था को जन्म दिया।

253. (B) अपनी क्षमता को साकार करने की स्वतंत्रता।
सकारात्मक स्वतंत्रता की अवधारणा व्यक्ति को केवल बाहरी प्रतिबंधों से मुक्त करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उसे उन साधनों और परिस्थितियों से लैस करने पर केंद्रित है जिनसे वह अपनी आंतरिक क्षमताओं को साकार कर सके। यह 'स्वयं का स्वामी होने' की स्वतंत्रता है, जहाँ व्यक्ति विवेक और आत्मनिर्भरता के माध्यम से अपना पूर्ण विकास करता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार, राज्य की भूमिका सक्रिय और सहायक होती है, जो शिक्षा, स्वास्थ्य और समानता के माध्यम से एक ऐसा वातावरण तैयार करती है जिसमें व्यक्ति वास्तव में स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने और कार्य करने के योग्य बन सके। यह स्वतंत्रता के विकासात्मक और सामाजिक आयाम को व्यक्त करता है।

254. (B) साधनों और साध्य की शुद्धता।
महात्मा गांधी का साध्य और साधन के संबंध में दिया गया सिद्धांत उनके संपूर्ण दर्शन का आधार है, जो साध्य के समान ही साधनों की शुद्धता पर अत्यधिक बल देता है। गांधीजी का मानना था कि साधन एक बीज की तरह हैं और साध्य एक पेड़ की तरह; यदि बीज अशुद्ध या हिंसक है, तो उससे प्राप्त परिणाम कभी भी न्यायपूर्ण या नैतिक नहीं हो सकता। उनके अनुसार, अच्छे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अनैतिक या हिंसक रास्तों का उपयोग करना स्वयं उस लक्ष्य की पवित्रता को नष्ट कर देता है। यह दृष्टिकोण राजनीतिक और सामाजिक संघर्ष को एक उच्च नैतिक साधना के रूप में पुनर्परिभाषित करता है जहाँ ईमानदारी और अहिंसा ही विजय के मार्ग हैं।

255. (B) केवल व्यक्तिगत योग्यता ही किसी की नियति निर्धारित करती है।
सामाजिक न्याय उस विचार की कड़ी आलोचना करता है जो यह मानता है कि व्यक्ति की नियति केवल उसकी अपनी योग्यता और प्रयासों से निर्धारित होती है। सामाजिक न्याय के समर्थकों का तर्क है कि व्यक्ति की सफलता में समाज की बुनियादी संरचना, विरासत में मिले अवसर और ऐतिहासिक परिस्थितियां एक बड़ी भूमिका निभाती हैं। यदि समाज में संसाधनों और अवसरों का वितरण असमान है, तो केवल 'योग्यता' के आधार पर प्रतिस्पर्धा करना उन लोगों के लिए अन्यायपूर्ण है जो पिछड़ेपन में पैदा हुए हैं। अतः सामाजिक न्याय एक निष्पक्ष सामाजिक धरातल तैयार करने की मांग करता है जहाँ योग्यता का मूल्यांकन वास्तविक समानता के संदर्भ में हो सके।

256. (A) लोकतांत्रिक केंद्रीयवाद
लेनिन के पार्टी सिद्धांत की सबसे प्रमुख विशेषता 'लोकतांत्रिक केंद्रीयवाद' है। यह सिद्धांत दो तत्वों का मिश्रण है: आंतरिक पार्टी चर्चाओं और चुनाव के स्तर पर 'लोकतंत्र', और एक बार निर्णय ले लिए जाने के बाद सभी सदस्यों द्वारा पूर्ण अनुशासन के साथ उसका पालन करने के स्तर पर 'केंद्रीयवाद'। लेनिन का मानना था कि एक क्रांतिकारी पार्टी को एक प्रभावी शक्ति के रूप में कार्य करने के लिए इस कठोर अनुशासन और एकीकृत नेतृत्व की अनिवार्य आवश्यकता है। यह ढांचा पार्टी को बाहरी खतरों के विरुद्ध मजबूत बनाता है और क्रांतिकारी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उसे एक अनुशासित सेना की तरह संचालित करता है।

257. (B) किसी विशेष विचारधारा का मजबूती से पालन करता है और उसे आगे बढ़ाता है।
एक विचारधारावादी वह व्यक्ति होता है जो किसी विशिष्ट राजनीतिक विचारधारा या विश्वासों के तंत्र के प्रति अत्यंत प्रतिबद्ध होता है और अपने कार्यों एवं निर्णयों को उसी के सिद्धांतों के अनुरूप संचालित करता है। वह न केवल उस विचारधारा में गहरा विश्वास रखता है, बल्कि वह उसे समाज में प्रसारित करने और उसे लागू करने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास भी करता है। विचारधारावादी के लिए उसकी विश्वदृष्टि ही वास्तविकता को समझने का एकमात्र सही माध्यम होती है। ऐसे व्यक्ति अक्सर राजनीतिक आंदोलनों और दलों के वैचारिक स्तंभ होते हैं, जो व्यवस्था को बनाए रखने या उसे बदलने के लिए जनमत को लामबंद करने का कार्य करते हैं।

258. (A) 1960 के दशक की उथल-पुथल की भविष्यवाणी करने में।
राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान को अक्सर व्यवहारवाद की उस गहरी विफलता की प्रतिक्रिया के रूप में देखा जाता है जिसमें वह 1960 के दशक की व्यापक सामाजिक उथल-पुथल, जैसे नागरिक अधिकार आंदोलन और वियतनाम युद्ध के विरोध को समझने में पूरी तरह असमर्थ रहा था। व्यवहारवाद के वैज्ञानिक मॉडल और आँकड़ा विश्लेषण इन आंदोलनों के पीछे छिपी नैतिक तीव्रता और न्याय की तड़प को पकड़ने में विफल रहे। इस संकट ने विद्वानों को यह एहसास कराया कि राजनीति का अध्ययन केवल सांख्यिकी नहीं है, बल्कि यह मूल्यों और मानवीय आकांक्षाओं का अध्ययन है, जिससे मानकीय सिद्धांत का महत्व फिर से स्थापित हुआ।

259. (B) निर्णय लेने में सभी नागरिकों का समान महत्व है।
राजनीतिक समानता का वास्तविक अर्थ यह है कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रत्येक नागरिक को शासन की निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करने का समान अवसर प्राप्त होना

Click Here to Buy book on Amazon

चाहिए। इसमें 'एक व्यक्ति, एक वोट' का सिद्धांत और प्रत्येक वोट का समान मूल्य होना अनिवार्य है। राजनीतिक समानता यह सुनिश्चित करती है कि शक्ति का वितरण किसी विशिष्ट वर्ग तक सीमित न रहे, बल्कि वह पूरी जनता में समान रूप से निहित हो। यह अवधारणा नागरिक संप्रभुता का आधार है और यह गारंटी देती है कि सरकार की नीतियां किसी भी भेदभाव के बिना सभी नागरिकों की समान भागीदारी और सहमति से निर्मित होंगी।

260. (D) I, II और III
समानता के ये तीनों रूप आधुनिक न्यायपूर्ण समाज के विभिन्न और महत्वपूर्ण आयामों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कानूनी समानता यह सुनिश्चित करती है कि कानून सभी पर बिना किसी भेदभाव के निष्पक्ष रूप से लागू हो। अवसर की समानता का लक्ष्य सामाजिक बाधाओं को हटाकर सभी को अपनी योग्यता सिद्ध करने का समान मंच प्रदान करना है। परिणाम की समानता समाज की गहरी आर्थिक विषमताओं को कम करने का प्रयास करती है ताकि सभी नागरिकों के लिए जीवन की आधारभूत स्थितियाँ समान हों। अतः ये तीनों सिद्धांत मिलकर वास्तविक समानता की एक व्यापक रूपरेखा तैयार करते हैं जो लोकतंत्र की आत्मा है।

261. (B) यूरोपीय मध्यकाल
दो तलवारों का सिद्धांत मुख्य रूप से यूरोपीय मध्यकाल के दौरान चर्च और राज्य के बीच के जटिल संबंधों को परिभाषित करने वाला सबसे केंद्रीय वैचारिक ढांचा था। इस युग में धर्म और राजनीति एक-दूसरे में गहराई से समाहित थे और समाज का पूरा संगठन ईसाई धर्म के सिद्धांतों पर आधारित था। यह सिद्धांत उस समय के शासन की वैधता और अधिकार क्षेत्र के विवादों को सुलझाने का मुख्य माध्यम बना। यद्यपि आधुनिक युग में चर्च और राज्य के पृथक्करण ने इसे अप्रासंगिक बना दिया, परंतु मध्यकालीन राजनीतिक इतिहास और दर्शन को समझने के लिए यह आज भी एक अनिवार्य आधार बना हुआ है।

262. (B) मूल्य-तटस्थता के कारण यथास्थिति का बचाव हुआ।
व्यवहारवाद की एक प्रमुख उत्तर-व्यवहारवादी आलोचना यह थी कि इसकी 'मूल्य-तटस्थता' और तथ्यों पर अत्यधिक ध्यान देने के कारण यह अनजाने में मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था या 'यथास्थिति' का बचाव करने लगा था। आलोचकों ने तर्क दिया कि जब विद्वान समाज की बुराइयों और अन्यायों के विरुद्ध नैतिक स्टैंड लेने से बचते हैं, तो वे वास्तव में वर्तमान सत्ता संरचना को ही मजबूती प्रदान करते हैं। उत्तर-व्यवहारवादियों के अनुसार, राजनीति विज्ञान को केवल यह नहीं बताना चाहिए कि 'क्या है', बल्कि उसे एक बेहतर समाज के निर्माण के लिए सक्रिय रूप से कार्य करना चाहिए, जो मूल्यों की उपेक्षा करके संभव नहीं है।

263. (B) संपत्ति और धन
महात्मा गांधी की 'न्यासधारिता' की अवधारणा संपत्ति और धन के प्रबंधन के बारे में एक अद्वितीय सामाजिक-आर्थिक सिद्धांत है। इसके अनुसार, संपन्न व्यक्तियों को अपनी अतिरिक्त संपत्ति का स्वामी नहीं, बल्कि समाज के लिए उसका 'न्यासी' समझना चाहिए। उन्हें उस धन का उपयोग अपनी विलासिता के लिए नहीं, बल्कि पूरे समुदाय, विशेषकर गरीबों के कल्याण के लिए करना चाहिए। यह सिद्धांत वर्ग संघर्ष के हिंसक मार्ग के स्थान पर हृदय परिवर्तन और नैतिक उत्तरदायित्व के माध्यम से आर्थिक असमानता को हल करने का एक अहिंसक विकल्प प्रस्तुत करता है, जो गांधीवादी आर्थिक दर्शन का केंद्र है।

264. (B) सामाजिक संस्थानों की बुनियादी संरचना।
सामाजिक न्याय की प्राथमिक चिंता समाज के संस्थानों, कानूनों और आर्थिक व्यवस्थाओं की समग्र संरचना की निष्पक्षता सुनिश्चित करना है। यह केवल व्यक्तिगत आचरण या एकल लेनदेन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देखती है कि समाज की बुनियादी व्यवस्थाएं किस प्रकार लाभों और बोझों का वितरण कर रही हैं। सामाजिक न्याय का लक्ष्य उन संरचनात्मक दोषों को दूर करना है जो कुछ समूहों को जन्मजात लाभ प्रदान करते हैं और दूसरों को पिछड़ा रखते हैं। यह एक ऐसी व्यवस्था की वकालत करता है जहाँ सामाजिक संस्थान बिना किसी भेदभाव के सभी के लिए न्याय, अवसर और संसाधनों की पहुँच सुनिश्चित कर सकें।

265. (B) कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर ही वर्ग संघर्ष जारी रहता है।
माओ जेदोंग की "स्थायी क्रांति" की अवधारणा शास्त्रीय मार्क्सवाद से इस अर्थ में अलग है कि उनके अनुसार समाजवाद की स्थापना और कम्युनिस्ट पार्टी के सत्ता में आने के बाद भी वर्ग संघर्ष समाप्त नहीं होता। माओ ने चेतावनी दी कि पार्टी के भीतर ही नौकरशाही और पूंजीवादी प्रवृत्तियाँ फिर से उभर सकती हैं, जो क्रांति के लक्ष्यों को भ्रष्ट कर सकती हैं। इसलिए, उन्होंने समाज को निरंतर क्रांतिकारी आंदोलनों के माध्यम से शुद्ध और सक्रिय रखने पर बल दिया। यह दृष्टिकोण मानता है कि समाजवाद की ओर यात्रा एक निरंतर चलने वाला वैचारिक युद्ध है जिसमें सतर्कता और जन-लामबंदी सदैव अनिवार्य है।

266. (A) मजबूत प्रक्रियात्मक लेकिन कमजोर सारवान लोकतंत्र।
एक ऐसी सरकार जहाँ स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव तो होते हैं, लेकिन निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास वास्तव में निर्णय लेने की शक्ति कम होती है, वह 'मजबूत प्रक्रियात्मक' लेकिन 'कमजोर सारवान' लोकतंत्र का उदाहरण है। यहाँ लोकतंत्र का बाहरी ढांचा और चुनावी प्रक्रियाएं तो प्रभावी ढंग से कार्य कर रही हैं, लेकिन शासन के वास्तविक परिणाम और जनता की इच्छा का प्रभावी क्रियान्वयन अत्यंत सीमित है। ऐसी व्यवस्था में नागरिकों को मतदान का अधिकार तो प्राप्त होता है, परंतु वह अधिकार वास्तविक नीतिगत परिवर्तनों या सत्ता पर प्रभावी नियंत्रण में परिवर्तित नहीं हो पाता, जो लोकतंत्र के असली उद्देश्य को अधूरा छोड़ देता है।

267. (B) अपनी शास्त्रीय विरासत के साथ संबंध।
राजनीतिक सिद्धांत के "पतन" का शोक उन विद्वानों ने व्यक्त किया जिन्हें लगा कि यह अनुशासन सुकरात, प्लेटो और अरस्तू जैसे विचारकों की महान शास्त्रीय विरासत से अपना नाता तोड़ रहा है। आलोचकों के अनुसार, आधुनिक राजनीति विज्ञान वैज्ञानिक पद्धतियों और आँकड़ा संचय में इतना अधिक उलझ

NODIA

गया कि उसने न्याय, सद्गुण और आदर्श समाज जैसे उन मौलिक प्रश्नों को उपेक्षित कर दिया जिन्होंने सदियों से राजनीतिक चिंतन को गहराई प्रदान की थी। इस पतन का अर्थ था सिद्धांत का अपनी दार्शनिक जड़ों से विमुख होना, जिससे वह समाज को नैतिक मार्गदर्शन देने की अपनी प्राथमिक क्षमता खो रहा था।

268. (A) राजनीतिक कार्रवाई के लिए लक्ष्य प्रदान करना।
विचारधारा का एक मुख्य घटक उसका 'अच्छे समाज' का दृष्टिकोण है, जो अनुयायियों को उनके भविष्य के लिए एक स्पष्ट और आकर्षक लक्ष्य प्रदान करता है। यह दृष्टिकोण केवल एक काल्पनिक स्वप्न नहीं है, बल्कि यह वर्तमान व्यवस्था की कमियों को दूर करने और एक बेहतर विकल्प के निर्माण के लिए राजनीतिक कार्रवाई को प्रेरित करता है। यह लोगों को यह बताता है कि वे किस लिए लड़ रहे हैं और उनके सामूहिक प्रयासों का अंतिम गंतव्य क्या होगा। यह साझा विजन ही विचारधारा को एक शक्तिशाली लामबंदी का उपकरण बनाता है जो समाज में बड़े बदलाव लाने के लिए जनशक्ति को एकजुट करता है।

269. (B) नकारात्मक स्वतंत्रता
मतदान को अनिवार्य बनाने वाला कानून संभवतः व्यक्ति की नकारात्मक स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है, क्योंकि यह व्यक्ति को वह कार्य करने के लिए मजबूर करता है जिसे वह शायद स्वेच्छा से न करना चाहे। नकारात्मक स्वतंत्रता व्यक्ति के निजी क्षेत्र में किसी भी बाहरी हस्तक्षेप या मजबूरी के अभाव पर बल देती है, जिसमें "कार्य न करने का अधिकार" भी शामिल है। यद्यपि अनिवार्य मतदान का उद्देश्य लोकतांत्रिक भागीदारी को बढ़ाना हो सकता है, परंतु नकारात्मक स्वतंत्रता के दृष्टिकोण से यह व्यक्ति की स्वायत्तता पर राज्य द्वारा लगाया गया एक अनुचित प्रतिबंध माना जा सकता है जो उसकी मर्जी के बिना लागू होता है।

270. (B) समर्पित पेशेवर क्रांतिकारियों से।
लेनिन के संगठनात्मक सिद्धांत के अनुसार, "अग्रगामी" पार्टी का गठन केवल आम श्रमिकों से नहीं, बल्कि अत्यंत समर्पित, अनुशासित और पेशेवर क्रांतिकारियों के एक छोटे समूह से होना चाहिए। लेनिन का मानना था कि क्रांति को सफल बनाने के लिए एक ऐसी पार्टी की आवश्यकता है जो क्रांतिकारी सिद्धांतों के प्रति पूर्णतः निष्ठावान हो और गुप्त एवं चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी कार्य करने में सक्षम हो। यह दल सर्वहारा वर्ग के राजनीतिक शिक्षक और नेतृत्वकर्ता के रूप में कार्य करता है, जो उन्हें संगठित कर पूंजीवादी सत्ता के विरुद्ध संघर्ष का वैज्ञानिक संचालन करता है।

271. (A) दो तलवारों का सिद्धांत
पोप बोनिफेस आठवीं और फ्रांस के राजा फिलिप चतुर्थ के बीच का ऐतिहासिक संघर्ष मध्यकालीन यूरोप में दो तलवारों के सिद्धांत की व्याख्या और अधिकार क्षेत्र को लेकर छिड़ा एक चरम विवाद था। यह संघर्ष इस प्रश्न पर केंद्रित था कि क्या सम्राट को चर्च की संपत्ति पर कर लगाने का अधिकार है और क्या पोप के पास राजाओं पर अंतिम अधिकार है। बोनिफेस आठवीं ने आध्यात्मिक तलवार की पूर्ण श्रेष्ठता का दावा किया, जबकि फिलिप ने राष्ट्रीय संप्रभुता का बचाव किया। यह घटना मध्यकालीन एकीकृत ईसाई समाज के पतन और आधुनिक संप्रभु राष्ट्रों के उदय की दिशा में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई।

272. (B) राजनीति में व्यक्तियों का अवलोकनीय व्यवहार।
व्यवहारवाद का मुख्य केंद्र राजनीति को औपचारिक संस्थानों और कानूनी दस्तावेजों के अध्ययन से हटाकर व्यक्तियों और समूहों के वास्तविक एवं अवलोकनीय व्यवहार पर केंद्रित करना है। व्यवहारवादियों का मानना था कि राजनीतिक व्यवस्था को वास्तव में समझने के लिए हमें यह देखना चाहिए कि लोग मतदान कैसे करते हैं, वे राजनीतिक गतिविधियों में कैसे भाग लेते हैं और वे शक्ति के प्रति किस प्रकार प्रतिक्रिया करते हैं। इस दृष्टिकोण ने राजनीति विज्ञान को एक वैज्ञानिक आधार प्रदान किया, जहाँ आँकड़ों और अनुभवजन्य साक्ष्यों के माध्यम से राजनीतिक प्रवृत्तियों का वस्तुनिष्ठ विश्लेषण करना संभव हो सका।

273. (B) कानूनी प्रणाली के भीतर अधिकार और निष्पक्ष व्यवहार।
'व्यक्तिगत न्याय' की अवधारणा मुख्य रूप से इस विचार पर केंद्रित है कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ कानूनी प्रणाली के भीतर बिना किसी भेदभाव के निष्पक्ष और गरिमापूर्ण व्यवहार होना चाहिए। यह विशेष रूप से कानून के समक्ष समानता, उचित कानूनी प्रक्रिया और व्यक्तियों के उन मौलिक अधिकारों की सुरक्षा पर बल देती है जिन्हें किसी भी परिस्थिति में छीना नहीं जा सकता। व्यक्तिगत न्याय का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके कार्यों और परिस्थितियों के आधार पर उसका उचित हक प्राप्त हो। यह उदारवादी न्याय व्यवस्था का केंद्र है जो व्यक्ति की स्वायत्तता का सम्मान करता है।

274. (B) एक न्यायपूर्ण उदार समाज के लिए आधार प्रदान करना।
जॉन रॉल्स ने अपनी कालजयी पुस्तक "न्याय का सिद्धांत" के माध्यम से एक ऐसे न्यायपूर्ण उदार समाज के लिए ठोस दार्शनिक आधार प्रदान करने का प्रयास किया जहाँ स्वतंत्रता और समानता के बीच सामंजस्य हो। उन्होंने 'अज्ञानता के पर्दे' जैसे मौलिक विचारों के माध्यम से यह तर्क दिया कि न्याय के सिद्धांत वे होने चाहिए जिन पर लोग बिना किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के सहमत हों। रॉल्स का कार्य विशेष रूप से समाज के सबसे कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करने और संसाधनों के उचित वितरण पर बल देता है, जिससे आधुनिक उदारवादी लोकतंत्रों को एक नई वैचारिक गहराई और दिशा प्राप्त हुई।

275. (A) मानवता की एकता और नैतिक अनुनय।
मार्क्सवादी वर्ग संघर्ष के विपरीत, महात्मा गांधी ने मानवता की मूल एकता और हृदय परिवर्तन के माध्यम से सामाजिक समस्याओं को सुलझाने पर ध्यान केंद्रित किया। उनका मानना था कि समाज के विभिन्न वर्गों के बीच स्थायी शांति और न्याय हिंसक संघर्ष से नहीं, बल्कि नैतिक अनुनय और आपसी समझ से ही संभव है। गांधीजी का सत्याग्रह और 'न्यासधारिता' का सिद्धांत इसी विश्वास पर आधारित है कि अमीर और गरीब, दोनों को एक-दूसरे के पूरक के रूप में देखा जाना चाहिए। यह दृष्टिकोण संघर्ष के स्थान पर सहयोग और नैतिक उत्थान को

Downloaded from www.pdf.tube

प्राथमिकता देता है, जो समाज को एकजुट करने का प्रयास करता है।

276. (C) सभी बच्चों को मुफ्त सार्वजनिक शिक्षा प्रदान करना।
सभी बच्चों को मुफ्त सार्वजनिक शिक्षा प्रदान करना अवसर की समानता को बढ़ावा देने वाली सबसे प्रभावशाली नीति है। शिक्षा वह आधारभूत माध्यम है जो व्यक्ति को अपनी प्रतिभा और क्षमता विकसित करने के योग्य बनाता है, जिससे वह समाज में अपनी योग्यता के अनुसार प्रगति कर सके। जन्म या आर्थिक स्थिति की बाधाओं को हटाकर शिक्षा का समान मंच प्रदान करना यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक बच्चे के पास अपने भविष्य को संवारने का एक निष्पक्ष और समान मौका हो। यह नीति सामाजिक गतिशीलता को बढ़ाती है और एक ऐसे न्यायपूर्ण समाज का निर्माण करती है जहाँ सफलता व्यक्ति के परिश्रम का परिणाम होती है।

277. (D) अलग-अलग समय पर सकारात्मक और नकारात्मक अर्थ।
"विचारधारा" शब्द का इतिहास अत्यंत रोचक रहा है और इसके अर्थ अलग-अलग समय पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रहे हैं। मूल रूप से इसे 'विचारों के विज्ञान' के रूप में एक सकारात्मक अर्थ में प्रस्तुत किया गया था। हालाँकि, कार्ल मार्क्स ने इसे 'भ्रामक चेतना' या शासक वर्ग के हितों की रक्षा करने वाले झूठे विश्वासों के रूप में एक नकारात्मक रूप प्रदान किया। बाद में, समाजशास्त्रियों ने इसे समाज की व्याख्या करने वाले विचारों के एक सुसंगत तंत्र के रूप में अधिक तटस्थ अर्थ में उपयोग करना शुरू किया। आज यह शब्द राजनीति में विश्वदृष्टि और क्रिया के ढांचे के रूप में एक व्यापक अर्थ में स्वीकार किया जाता है।

278. (B) संशोधनवाद से लड़ने और अपने दृष्टिकोण को फिर से स्थापित करने के लिए।
माओ जेदोंग द्वारा 'सांस्कृतिक क्रांति' की शुरुआत का मुख्य उद्देश्य चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और प्रशासन के भीतर पनप रहे 'संशोधनवाद' और नौकरशाही प्रवृत्तियों को समाप्त करना था। माओ का मानना था कि पार्टी के कुछ नेता क्रांतिकारी मार्ग से भटककर पूंजीवादी और विशेषाधिकार प्राप्त जीवन अपना रहे हैं, जिससे समाजवाद को खतरा है। उन्होंने युवाओं और जनता को अपने क्रांतिकारी दृष्टिकोण को फिर से स्थापित करने और समाज को निरंतर क्रांतिकारी संघर्ष की भावना से भरने के लिए लामबंद किया। यह आंदोलन माओ द्वारा अपनी विचारधारा और सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण बनाए रखने का एक अत्यंत व्यापक प्रयास था।

279. (B) दबावपूर्ण मुद्दों के साथ जुड़ना और उन्हें हल करना चाहिए।
उत्तर-व्यवहारवाद में 'प्रासंगिकता' की मांग का तात्पर्य यह था कि राजनीतिक वैज्ञानिकों की यह नैतिक जिम्मेदारी है कि वे समकालीन समाज के दबावपूर्ण और ज्वलंत मुद्दों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ें। शोध को केवल बौद्धिक संतुष्टि तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसे नस्लवाद, युद्ध, गरीबी और परमाणु संकट जैसी वास्तविक मानवीय समस्याओं का समाधान खोजने के लिए निर्देशित होना चाहिए। उत्तर-व्यवहारवादियों ने तर्क दिया कि यदि ज्ञान समाज की सेवा नहीं कर सकता, तो उसकी वैज्ञानिकता का कोई मूल्य नहीं है। यह दृष्टिकोण अकादमिक जगत को सामाजिक जिम्मेदारी और क्रियाशील ज्ञान की दिशा में मोड़ने का आह्वान था।

NODIA

280. (B) जनता में।
लोकप्रिय संप्रभुता का सिद्धांत आधुनिक लोकतंत्र का मूलाधार है, जिसका अर्थ है कि अंतिम राजनीतिक अधिकार और शक्ति का स्रोत किसी राजा, संस्था या वर्ग में नहीं, बल्कि संपूर्ण जनता में निहित है। इसके अनुसार, सरकार की वैधता और उसकी शक्तियों का आधार शासितों की सहमति है। नागरिक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के माध्यम से अपनी संप्रभुता का प्रयोग करते हैं और प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। यदि कोई सरकार जनता की इच्छा का उल्लंघन करती है, तो नागरिकों को उसे बदलने या हटाने का नैतिक अधिकार होता है। यह सिद्धांत व्यक्ति की गरिमा और जन-इच्छा की सर्वोपरिता को स्थापित करता है।

281. (B) दावों में अतिव्याप्ति हुई, जिससे संघर्ष हुआ।
दो तलवारों का सिद्धांत चर्च और राज्य के बीच एक स्पष्ट और स्थायी विभाजन बनाने में इसलिए विफल रहा क्योंकि व्यवहार में दोनों सत्ताओं के अधिकार क्षेत्रों और दावों में निरंतर अतिव्याप्ति बनी रही। आध्यात्मिक मामले अक्सर सांसारिक हितों को प्रभावित करते थे और लौकिक नीतियां चर्च की स्वायत्तता को चुनौती देती थीं। चूँकि दोनों पक्ष अपनी सर्वोच्चता का दावा करते थे और एक-दूसरे के कार्यक्षेत्रों में हस्तक्षेप करते थे, इसलिए यह सिद्धांत शांति के बजाय निरंतर विवादों और सत्ता संघर्ष का स्रोत बन गया। इस वैचारिक द्वंद्व ने ही अंततः आधुनिक संप्रभुता और धर्मनिरपेक्षता की नई अवधारणाओं की आवश्यकता को जन्म दिया।

282. (C) गांधीवादी सिद्धांत
गांधीवादी सिद्धांत मौलिक रूप से व्यक्तियों के आंतरिक नैतिक परिवर्तन और वैकल्पिक विकेंद्रीकृत संस्थानों, जैसे ग्राम स्वराज के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करता है। गांधीजी का मानना था कि वास्तविक सामाजिक सुधार केवल ऊपर से कानूनों को थोपने से नहीं, बल्कि व्यक्ति के आत्म-सुधार और चरित्र निर्माण से ही संभव है। उन्होंने केंद्रीकृत राज्य सत्ता पर निर्भरता के बजाय आत्मनिर्भर ग्रामीण समुदायों और स्वैच्छिक सहयोग की वकालत की। यह दृष्टिकोण समाज के पुनर्गठन के लिए एक नीचे से ऊपर की प्रक्रिया प्रस्तुत करता है, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति की नैतिक शक्ति और स्थानीय स्वायत्तता ही न्यायपूर्ण व्यवस्था का आधार बनती है।

283. (B) एक अधिकार किसी और पर कर्तव्य थोपता है।
राजनीतिक और कानूनी सिद्धांतों में एक 'अधिकार' केवल एक 'स्वतंत्रता' से इसलिए भिन्न होता है क्योंकि अधिकार अनिवार्य रूप से किसी अन्य व्यक्ति या राज्य पर एक प्रतिगामी कर्तव्य थोपता है। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास शिक्षा का अधिकार है, तो यह राज्य पर आपको वह सुविधा प्रदान करने का कर्तव्य डालता है। इसके विपरीत, एक स्वतंत्रता का अर्थ केवल वह कार्य करने की अनुमति है जहाँ दूसरों पर कोई विशेष कर्तव्य नहीं होता, सिवाय हस्तक्षेप न करने के। यह

सूक्ष्म अंतर अधिकारों की सामाजिक और कानूनी सुरक्षा की गहराई को स्पष्ट करता है, जो नागरिकों को व्यवस्था के भीतर दावा करने की शक्ति प्रदान करता है।

284. (B) जो कथन अनुभवजन्य रूप से सत्यापन योग्य नहीं हैं, वे अर्थहीन हैं।
तार्किक प्रत्यक्षवाद का मूल मंत्र यह विश्वास था कि केवल वही कथन सार्थक और ज्ञानवर्धक हैं जिन्हें या तो तार्किक रूप से सिद्ध किया जा सके या अनुभवजन्य रूप से सत्यापित किया जा सके। इस दृष्टिकोण ने मूल्य-आधारित कथनों, जैसे "न्याय अच्छा है" या "स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है", को वैज्ञानिक रूप से 'अर्थहीन' मान लिया, क्योंकि उनका कोई भौतिक सत्यापन संभव नहीं था। इसी विचारधारा ने बीसवीं शताब्दी के मध्य में राजनीतिक सिद्धांत को केवल तथ्यों और सांख्यिकी तक सीमित कर दिया था, जिससे मानकीय दर्शन का ह्रास हुआ और राजनीति विज्ञान में एक वैचारिक शून्य पैदा हो गया था।

285. (B) लोगों को सामूहिक कार्रवाई करने के लिए राजी करना।
विचारधारा का 'लामबंदी' कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह लोगों के बिखरे हुए विचारों और असंतोष को एक दिशा प्रदान करती है और उन्हें सामूहिक राजनीतिक कार्रवाई करने के लिए राजी करती है। एक विचारधारा साझा लक्ष्यों, प्रतीकों और नारों के माध्यम से जनता को एकजुट करती है और उनमें यह विश्वास पैदा करती है कि उनके प्रयासों से समाज में वांछित परिवर्तन लाया जा सकता है। यह लोगों को सड़कों पर उतरने, मतदान करने या किसी आंदोलन में भाग लेने के लिए आवश्यक प्रेरणा और तार्किक आधार प्रदान करती है। लामबंदी के बिना कोई भी विचारधारा केवल एक मृत सिद्धांत बनी रहती है और वास्तविक सामाजिक शक्ति नहीं बन पाती।

286. (B) लाभों और बोझों का उचित वितरण करना।
सामाजिक न्याय का मौलिक और सर्वोच्च लक्ष्य समाज के सदस्यों के बीच उसके लाभों और बोझों का उचित और तर्कसंगत वितरण सुनिश्चित करना है। यह इस विचार पर आधारित है कि समाज के संस्थानों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाना चाहिए कि कोई भी वर्ग या समूह अन्यायपूर्ण रूप से पीछे न रहे। सामाजिक न्याय केवल औपचारिक समानता से आगे बढ़कर उन संरचनात्मक असमानताओं को दूर करने का प्रयास करता है जो ऐतिहासिक रूप से समाज में व्याप्त रही हैं। इसका उद्देश्य एक ऐसी निष्पक्ष और संतुलित व्यवस्था बनाना है जहाँ प्रत्येक व्यक्ति को अपनी गरिमा के साथ विकास का अवसर मिले।

287. (C) रणनीतिक आक्रामक
माओ जेदोंग के "जनयुद्ध" के सिद्धांत के अनुसार, सशस्त्र संघर्ष तीन प्रमुख चरणों से होकर गुजरता है: रणनीतिक रक्षात्मक, रणनीतिक गतिरोध और अंत में "रणनीतिक आक्रामक"। रणनीतिक आक्रामक अंतिम और निर्णायक चरण है जहाँ क्रांतिकारी सेना इतनी शक्तिशाली और संगठित हो जाती है कि वह दुश्मन की मुख्य शक्तियों पर सीधा हमला कर सकती है और शहरों तथा प्रमुख केंद्रों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर सकती है। यह चरण क्रांति की पूर्ण विजय और नई सत्ता की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करता है। यह पूरी प्रक्रिया जनसमर्थन और परिस्थितियों के परिपक्व होने पर आधारित एक लंबी अवधि की रणनीति है।

288. (A) नकारात्मक स्वतंत्रता और सार्वजनिक कल्याण।
सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंधित करने का निर्णय नकारात्मक स्वतंत्रता और सार्वजनिक कल्याण के बीच के संघर्ष को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। नकारात्मक स्वतंत्रता के दृष्टिकोण से, एक व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार कार्य करने की छूट होनी चाहिए। हालाँकि, राज्य इस स्वतंत्रता को इसलिए सीमित करता है क्योंकि धूम्रपान दूसरों को प्रत्यक्ष हानि पहुँचाता है और सार्वजनिक स्वास्थ्य को खतरे में डालता है। यह उदाहरण जे.एस. मिल के 'क्षति के सिद्धांत' का एक आधुनिक अनुप्रयोग है, जहाँ किसी की स्वतंत्रता को केवल तभी बाधित किया जा सकता है जब वह दूसरों के अधिकारों या कल्याण के लिए नुकसानदायक साबित हो रही हो।

289. (B) शासन करने और युद्ध करने की धर्मनिरपेक्ष शक्ति।
मध्यकालीन दो तलवारों के सिद्धांत में 'लौकिक तलवार' राजाओं, सम्राटों और धर्मनिरपेक्ष शासकों के उस अधिकार का प्रतीक थी जो सांसारिक व्यवस्था बनाए रखने, न्याय करने और समाज की रक्षा के लिए युद्ध करने से संबंधित था। यह शक्ति भौतिक जगत के शासन और दंड देने के अधिकार से जुड़ी थी। लौकिक तलवार को आध्यात्मिक तलवार का पूरक माना गया था, जिसका कार्य चर्च के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक सुरक्षित और व्यवस्थित वातावरण तैयार करना था। यद्यपि यह भौतिक शक्ति का प्रतीक थी, परंतु मध्यकालीन चिंतन में इसे अक्सर आध्यात्मिक सत्ता के नैतिक मार्गदर्शन के अधीन माना गया।

290. (B) समाज को बेहतर बनाने के लिए ज्ञान का उपयोग करना।
उत्तर-व्यवहारवाद के "कार्य" पर दिए गए विशेष जोर ने यह स्पष्ट संदेश दिया कि राजनीतिक वैज्ञानिकों का यह मौलिक कर्तव्य है कि वे अपने वैज्ञानिक ज्ञान का उपयोग समाज को बेहतर बनाने और मानवीय संकटों को सुलझाने के लिए करें। केवल अकादमिक चर्चाओं या आँकड़ा संचय में संलिप्त रहना पर्याप्त नहीं है; विद्वानों को अपनी शोध प्राथमिकताओं को सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप ढालना चाहिए। ज्ञान को सक्रिय सामाजिक सुधार और न्याय की स्थापना का माध्यम होना चाहिए। यह दृष्टिकोण राजनीति विज्ञान को एक सक्रिय माध्यम के रूप में पुनर्परिभाषित करता है।

291. (C) नष्ट करके प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए।
लेनिन का यह अडिग विश्वास था कि पुराने बुर्जुआ राज्य तंत्र को केवल शांतिपूर्ण सुधारों के माध्यम से नहीं बदला जा सकता, बल्कि उसे क्रांतिकारी हिंसा के माध्यम से पूरी तरह नष्ट किया जाना चाहिए। लेनिन के अनुसार, यह राज्य तंत्र शोषकों का हथियार है, इसलिए इसे उखाड़ फेंककर उसके स्थान पर एक नया सर्वहारा राज्य स्थापित करना अनिवार्य है। यह नया राज्य संक्रमणकालीन होगा जो पूंजीवादी अवशेषों को समाप्त करेगा और अंततः एक ऐसे कम्युनिस्ट समाज की ओर ले जाएगा जहाँ राज्य की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। यह विचार क्रमिक

Click Here to Buy book on Amazon

सुधारवाद के विरुद्ध आमूल-चूल क्रांतिकारी परिवर्तन की वकालत करता है।

292. (A) एक स्वस्थ प्रक्रियात्मक लोकतंत्र।
एक स्वतंत्र प्रेस और सक्रिय विपक्षी दलों का अस्तित्व एक स्वस्थ और कार्यात्मक प्रक्रियात्मक लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण संकेतक माने जाते हैं। ये तत्व यह सुनिश्चित करते हैं कि चुनावी प्रक्रिया केवल औपचारिक न हो, बल्कि नागरिकों के पास सूचना के वैकल्पिक स्रोत हों और वे शासन की आलोचना करने में सक्षम हों। विपक्ष सरकार को जवाबदेह बनाता है और सत्ता के दुरुपयोग पर नियंत्रण रखता है। यद्यपि ये तत्व सारवान न्याय की पूर्ण गारंटी नहीं देते, परंतु वे उन संस्थागत सुरक्षा उपायों और नियमों को मजबूती प्रदान करते हैं जो किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की पारदर्शिता और स्थिरता के लिए अनिवार्य आधारशिला हैं।

293. (C) इतिहास के चालक के रूप में वर्ग संघर्ष
इतिहास को केवल वर्ग संघर्ष के परिणाम के रूप में देखना मार्क्सवादी विचारधारा का मूल तत्व है, जिसे महात्मा गांधी ने कभी स्वीकार नहीं किया। गांधीजी का मानना था कि समाज का विकास हिंसक संघर्ष के बजाय सहयोग, प्रेम और मानवता की मूल एकता पर आधारित है। उनके दर्शन के मुख्य स्तंभ स्वराज, सर्वोदय और अहिंसा हैं। वे मानते थे कि वर्ग भेदों को हृदय परिवर्तन और 'न्यासधारिता' जैसे नैतिक साधनों के माध्यम से शांतिपूर्ण ढंग से हल किया जा सकता है। अतः वर्ग संघर्ष की अवधारणा गांधीजी के नैतिक और आध्यात्मिक राजनीतिक दृष्टिकोण के पूर्णतः विपरीत है।

294. (C) उदार-संवैधानिकवाद
"कानून के समक्ष समानता" की अवधारणा उदार-संवैधानिकवाद की एक अनिवार्य आधारशिला है, जो यह सुनिश्चित करती है कि शासन कानूनों के अनुसार हो, न कि व्यक्तियों की मर्जी के अनुसार। यह सिद्धांत गारंटी देता है कि किसी भी नागरिक को उसकी सामाजिक स्थिति या धन के आधार पर विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होंगे और प्रत्येक व्यक्ति को समान कानूनी सुरक्षा प्राप्त होगी। यह अवधारणा राज्य की मनमानी शक्ति पर अंकुश लाती है और व्यक्तिगत अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं के संरक्षण के लिए एक निष्पक्ष कानूनी ढांचा प्रदान करती है। उदारवादी लोकतंत्रों की सफलता और उनकी न्यायपूर्ण प्रकृति इसी सिद्धांत की दृढ़ता पर निर्भर करती है।

295. (B) मानकीय प्रश्नों में नए सिरे से विश्वास।
राजनीतिक सिद्धांत का "पुनरुत्थान" मुख्य रूप से न्याय, अधिकार, स्वतंत्रता और नैतिकता जैसे मानकीय और दार्शनिक प्रश्नों की ओर लौटने और उनमें नए सिरे से अटूट विश्वास प्रकट करने के माध्यम से चिह्नित किया गया था। व्यवहारवाद के दौर में इन विषयों को 'अवैज्ञानिक' मानकर उपेक्षित किया गया था, परंतु बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जॉन रॉल्स और अन्य विचारकों के कार्यों ने यह सिद्ध किया कि राजनीति के नैतिक आधारों पर चर्चा करना समाज को दिशा देने के लिए अनिवार्य है। इस पुनरुत्थान ने राजनीतिक चिंतन को फिर से एक अर्थपूर्ण और मूल्य-आधारित विमर्श बनाया जो मानवीय अस्तित्व के संकटों को संबोधित करता है।

296. (B) एक मुख्य अंतर्विरोध प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाता है।
माओ जेदोंग की प्रसिद्ध कृति "अंतर्विरोध पर" का केंद्रीय तर्क यह है कि समाज और प्रकृति में अंतर्विरोध सदैव विद्यमान रहते हैं और उनमें से एक 'मुख्य अंतर्विरोध' होता है जो विकास की पूरी प्रक्रिया को निर्देशित करता है। माओ का मानना था कि ऐतिहासिक परिस्थितियों के अनुसार मुख्य अंतर्विरोध बदलता रहता है और एक कुशल क्रांतिकारी का कार्य उस मुख्य अंतर्विरोध को पहचानना और उसे हल करने के लिए संघर्ष को केंद्रित करना है। यह दृष्टिकोण द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की एक मौलिक व्याख्या है, जिसने माओ को विभिन्न राजनीतिक परिस्थितियों में सटीक रणनीतियाँ बनाने और जनशक्ति को सही दिशा में लामबंद करने में मदद की।

297. (B) आध्यात्मिक और लौकिक अधिकार का आपस में जुड़ा होना।
मध्यकाल में एक राजनीतिक उपकरण के रूप में 'बहिष्करण' का प्रभावी उपयोग यह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है कि उस समय आध्यात्मिक और लौकिक अधिकार क्षेत्र कितने गहराई से एक-दूसरे से जुड़े हुए थे। जब पोप किसी राजा को चर्च से बहिष्कृत करते थे, तो वह न केवल एक धार्मिक दंड था, बल्कि इसके गंभीर राजनीतिक परिणाम भी होते थे, जैसे कि राजा की प्रजा को उसके प्रति वफादारी की शपथ से मुक्त कर देना। यह दर्शाता था कि आध्यात्मिक सत्ता के पास लौकिक संप्रतिक्रियाएँ उत्पन्न करने की जबरदस्त शक्ति थी, जिसने चर्च को मध्यकालीन राजनीति का एक अत्यंत शक्तिशाली और अपरिहार्य अंग बना दिया था।

298. (C) कोई तथ्य से मूल्य प्राप्त नहीं कर सकता।
तथ्य-मूल्य द्विभाजन का सिद्धांत यह प्रतिपादित करता है कि अनुभवजन्य तथ्यों और मानकीय मूल्यों के बीच एक तार्किक खाई मौजूद है। इसके अनुसार, केवल यह जानकर कि दुनिया में क्या हो रहा है, हम यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि क्या होना चाहिए, क्योंकि मूल्य व्यक्तिगत धारणाओं और नैतिकता पर आधारित होते हैं। व्यवहारवादियों ने इसी आधार पर तर्क दिया कि राजनीति विज्ञान को केवल तथ्यों के वस्तुनिष्ठ अध्ययन तक सीमित रहना चाहिए। यह अलगाव वैज्ञानिक जांच को व्यक्तिपरक निर्णयों से बचाने के उद्देश्य से किया गया था ताकि निष्कर्षों में सार्वभौमिकता और निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सके।

NODIA

299. (B) क्या समूहों में अवसरों का वितरण निष्पक्ष है?
सामाजिक न्याय की अवधारणा व्यक्तिगत कानूनी मामलों से कहीं अधिक व्यापक है और वह मुख्य रूप से समाज की संरचनात्मक निष्पक्षता से संबंधित है। यह इस प्रश्न पर केंद्रित है कि क्या समाज के विभिन्न समूहों और वर्गों के बीच संसाधनों, धन, शिक्षा और अवसरों का वितरण न्यायपूर्ण और तर्कसंगत है। सामाजिक न्याय का लक्ष्य उन बाधाओं को हटाना है जो किसी विशिष्ट वर्ग को प्रगति करने से रोकती हैं। यह समाज के लाभों और बोझों के पुनर्वितरण की मांग करता है ताकि

ऐतिहासिक रूप से वंचित समूहों को भी समान विकास का मौका मिले, जो एक संतुलित और न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की आधारशिला है।

300. (B) लेनिन ने हिंसक कब्जे की मांग की; गांधी ने अहिंसा की मांग की।
लेनिन और गांधी दोनों ही विशाल जनशक्ति को लामबंद करने में सफल रहे, परंतु उनके क्रांतिकारी दर्शन और साधनों के बीच एक मौलिक अंतर था। लेनिन ने पूंजीवादी राज्य को उखाड़ फेंककर सत्ता प्राप्त करने के लिए सशस्त्र विद्रोह और हिंसा को एक अनिवार्य और जायज उपकरण माना। इसके विपरीत, महात्मा गांधी ने संपूर्ण जन लामबंदी को सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर आधारित किया। उनका मानना था कि वास्तविक स्वराज केवल अहिंसक सत्याग्रह और नैतिक बल के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। यह वैचारिक अंतर संघर्ष के स्वरूप, नेतृत्व की प्रकृति और भविष्य के समाज की नैतिक नींव को गहराई से प्रभावित करता है।

www.nodia.in

NODIA

अध्याय 03
तुलनात्मक राजनीति

1. निम्नलिखित में से कौन तुलनात्मक राजनीति की 'प्रकृति' को सबसे अच्छी तरह परिभाषित करता है?
(A) अंतर्राष्ट्रीय संधियों और संगठनों का अध्ययन।
(B) घरेलू राजनीतिक प्रणालियों का आनुभविक अध्ययन और तुलना।
(C) पश्चिमी लोकतांत्रिक संविधानों का विशेष विश्लेषण।
(D) एकल राष्ट्र के राजनीतिक विकास का ऐतिहासिक विवरण।

2. तुलनात्मक राजनीति के पारंपरिक दृष्टिकोण की मुख्य विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी थी?
(A) यह काफी हद तक आदर्शात्मक और वर्णनात्मक था।
(B) यह मात्रात्मक डेटा और सांख्यिकीय विश्लेषण पर अत्यधिक निर्भर था।
(C) यह व्यक्तियों और समूहों के राजनीतिक व्यवहार पर केंद्रित था।
(D) इसने गैर-पश्चिमी, विकासशील देशों के अध्ययन पर जोर दिया।

3. व्यवस्था सिद्धांत के संदर्भ में, 'आगत' और 'समर्थन' क्या गठित करते हैं?
(A) राजनीतिक व्यवस्था के निर्गत।
(B) रूपांतरण प्रक्रिया।
(C) राजनीतिक व्यवस्था में आगत।
(D) फीडबैक लूप तंत्र।

4. संसदीय प्रणाली में विधायिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
(A) विधायिका वह स्रोत है जिससे राजनीतिक कार्यपालिका का गठन होता है।
(B) कार्यपालिका सीधे और सामूहिक रूप से विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है।
(C) राष्ट्राध्यक्ष सरकार के प्रमुख की सलाह पर विधायिका को भंग कर सकता है।
(D) विधायिका और कार्यपालिका शक्तियों के सख्त पृथक्करण के तहत कार्य करते हैं।

5. राजनीतिक विकास अक्सर तीन मुख्य विषयों से जुड़ा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है?
(A) समानता
(B) क्षमता
(C) क्रांति
(D) विभेदीकरण

6. नीचे दो कथन दिए गए हैं:
कथन I: राजनीतिक समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने राजनीतिक विश्वासों और मूल्यों को प्राप्त करते हैं।
कथन II: परिवार को अक्सर राजनीतिक समाजीकरण का प्राथमिक अभिकर्ता माना जाता है।
(A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं।
(C) कथन I सत्य है, लेकिन कथन II असत्य है।
(D) कथन I असत्य है, लेकिन कथन II सत्य है।

7. 'अभिजन का संचलन' की अवधारणा सबसे प्रसिद्ध रूप से किस राजनीतिक विचारक से जुड़ी है?
(A) गेटानो मोस्का
(B) रॉबर्ट मिचल्स
(C) सी. राइट मिल्स
(D) विल्फ्रेडो पेरेटो

8. तुलनात्मक राजनीति के विकास के निम्नलिखित चरणों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें:
1. संस्थानों का औपचारिक-कानूनी अध्ययन।
2. राजनीतिक क्रियाओं पर केंद्रित व्यवहारवादी क्रांति।
3. राजनीतिक अर्थव्यवस्था और तर्कसंगत चयन दृष्टिकोणों का उदय।
4. प्रासंगिकता और कार्रवाई पर उत्तर-व्यवहारवादी जोर।

(A) 1, 2, 4, 3
(B) 1, 3, 2, 4
(C) 2, 1, 3, 4
(D) 4, 3, 1, 2

9. तुलनात्मक राजनीति का कौन सा दृष्टिकोण विभिन्न राजनीतिक संरचनाओं द्वारा किए जाने वाले कार्यों, जैसे हित प्रकटीकरण और हित समूहन पर केंद्रित है?
(A) मार्क्सवादी दृष्टिकोण
(B) व्यवस्था दृष्टिकोण
(C) संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण
(D) पारंपरिक दृष्टिकोण

10. किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में न्यायपालिका का प्राथमिक कार्य क्या है?
(A) कानूनों की व्याख्या करना और विवादों का निपटारा करना।
(B) कानून बनाना और उन्हें लागू करना।

Downloaded from www.pdf.tube

(C) कानूनों को लागू करना और उनका पालन कराना।
(D) जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व करना।

11. राजनीतिक आधुनिकीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह अक्सर संस्कृति के धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया द्वारा विशेषीकृत होता है।
2. इसमें राजनीतिक व्यवस्था के भीतर संरचनात्मक विभेदीकरण में वृद्धि शामिल है।
3. यह सार्वभौमिक रूप से स्थिर लोकतांत्रिक परिणामों की ओर ले जाता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3

12. 'राजनीतिक संस्कृति' शब्द का तात्पर्य निम्नलिखित में से किससे है?
(A) किसी राज्य का औपचारिक संवैधानिक ढांचा।
(B) राजनीति के प्रति किसी जनसंख्या की सामूहिक अभिवृत्तियाँ, विश्वास और मूल्य।
(C) सत्तारूढ़ सरकार द्वारा प्रचारित आधिकारिक विचारधारा।
(D) राजनीतिक दलों और चुनावों को नियंत्रित करने वाले कानूनों का समूह।

13. गेटानो मोस्का ने तर्क दिया कि सभी समाज लोगों के दो वर्गों में विभाजित हैं। वे क्या हैं?
(A) बुर्जुआ और सर्वहारा।
(B) शेर और लोमड़ी।
(C) राजनीतिक वर्ग और जनसमूह।
(D) शक्ति अभिजन और जनता।

14. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।
अभिकथन (A): द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तुलनात्मक राजनीति के दायरे का काफी विस्तार हुआ ताकि विकासशील देशों के अध्ययन को शामिल किया जा सके।
कारण (R): वि-औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया ने एशिया और अफ्रीका में बड़ी संख्या में नए राज्यों का निर्माण किया, जो तुलनात्मक विश्लेषण के लिए नए केंद्र बन गए।
(A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(D) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

15. राज्य के अध्ययन के प्रति मार्क्सवादी दृष्टिकोण का मूल तर्क क्या है?
(A) राज्य शासक वर्ग के हितों के प्रबंधन का एक साधन है।
(B) राज्य प्रतिस्पर्धी सामाजिक समूहों के बीच एक तटस्थ मध्यस्थ है।
(C) राज्य का प्राथमिक कार्य शक्ति संतुलन बनाए रखना है।
(D) राज्य पूरे समाज की जरूरतों को पूरा करने के लिए स्वाभाविक रूप से विकसित होता है।

NODIA

16. सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली में, कार्यपालिका की विशेषता किस लक्षण से होती है?
(A) कार्यकारी और विधायी शक्तियों का संलयन।
(B) एक अलग, लोकप्रिय जनादेश और कार्यालय का एक निश्चित कार्यकाल।
(C) विधायिका के निचले सदन के प्रति जवाबदेही।
(D) सरकार के प्रमुख के रूप में एक प्रधानमंत्री की उपस्थिति।

17. संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक ढांचे में निम्नलिखित में से किसे 'आगत कार्य' माना जाता है?
(A) नियम निर्माण
(B) हित प्रकटीकरण
(C) नियम अनुप्रयोग
(D) नियम अधिनिर्णयन

18. "अल्पतंत्र का लौह नियम", जो यह प्रतिपादित करता है कि संगठन के सभी रूपों में अंततः अल्पतांत्रिक प्रवृत्तियाँ विकसित होंगी, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था?
(A) रॉबर्ट मिचल्स
(B) विल्फ्रेडो पेरेटो
(C) सी. राइट मिल्स
(D) गेटानो मोस्का

19. निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक समाजीकरण का एक विशिष्ट अभिकर्ता नहीं है?
(A) परिवार
(B) शैक्षणिक संस्थान
(C) आनुवंशिक प्रवृत्ति
(D) जनसंचार माध्यम

20. सूची I को सूची II के साथ सुमेलित करें।
सूची I: (अवधारणा)
P. व्यवस्था सिद्धांत
Q. संरचनात्मक प्रकार्यवाद
R. राजनीतिक विकास के संकट
S. आधार और अधिसंरचना
सूची II: (प्रतिपादक)
1. गैब्रियल आलमंड
2. डेविड ईस्टन
3. कार्ल मार्क्स
4. लुसियन पाई
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:
(A) P-2, Q-1, R-4, S-3
(B) P-1, Q-2, R-3, S-4
(C) P-2, Q-4, R-1, S-3
(D) P-3, Q-1, R-4, S-2

21. तुलनात्मक राजनीति में वर्णनात्मक, संस्था-केंद्रित अध्ययन से अधिक वैज्ञानिक, व्यवहार-केंद्रित अध्ययन की ओर बदलाव को किस रूप में जाना जाता है?
(A) परंपरावादी क्रांति
(B) उत्तर-आधुनिक मोड़
(C) व्यवहारवादी क्रांति
(D) संविधानवादी आंदोलन

22. राजनीतिक संस्कृति के वर्गीकरण में, किस प्रकार की विशेषता यह है कि नागरिक राजनीतिक व्यवस्था के प्रति जागरूक होते हैं लेकिन उससे निष्क्रिय प्रजा के रूप में संबंधित होते हैं?
(A) संकीर्ण संस्कृति
(B) प्रजाभावी संस्कृति
(C) सहभागी संस्कृति
(D) उदासीन संस्कृति

23. द्विसदनीय विधायिकाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
(A) वे सार्वभौमिक रूप से सभी संघीय राज्यों में पाए जाते हैं।
(B) इनमें एक ही विधायी सदन होता है।
(C) वे कानून पारित करने में हमेशा एकसदनीय विधायिकाओं की तुलना में अधिक कुशल होते हैं।
(D) दूसरा सदन अक्सर उप-राष्ट्रीय इकाइयों को प्रतिनिधित्व प्रदान करता है।

24. राजनीतिक आधुनिकीकरण सिद्धांत में एक प्रमुख अवधारणा 'विभेदीकरण' है। यह किसे संदर्भित करता है?
(A) राजनीतिक भूमिकाओं और संस्थानों का विशिष्टीकरण।
(B) धनी और निर्धन के बीच बढ़ती खाई।
(C) जातीय समूहों के बीच सांस्कृतिक विभाजन।
(D) औपनिवेशिक शक्ति से किसी राज्य का अलगाव।

25. लोकतंत्र का अभिजनवादी सिद्धांत लोकतंत्र को मुख्य रूप से किस रूप में परिभाषित करता है?
(A) निर्णय लेने में प्रत्यक्ष और निरंतर जन भागीदारी पर आधारित प्रणाली।
(B) कॉर्पोरेट और सैन्य क्षेत्रों के एक एकीकृत शक्ति अभिजन द्वारा शासित समाज।
(C) मतों के लिए प्रतिस्पर्धी संघर्ष के माध्यम से नेताओं को चुनने की एक प्रक्रियात्मक विधि।
(D) एक ऐसी व्यवस्था जहाँ जनता बिना प्रतिनिधित्व के सभाओं के माध्यम से सीधे शासन करती है।

26. राजनीतिक व्यवस्थाओं के संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक विश्लेषण में निम्नलिखित में से कौन सा एक 'निर्गत कार्य' है?
(A) नियम अनुप्रयोग
(B) राजनीतिक समाजीकरण
(C) हित समूहन
(D) राजनीतिक संचार

27. 'राजनीतिक सूत्र' की अवधारणा गेटानो मोस्का द्वारा किसे समझाने के लिए प्रस्तुत की गई थी?
(A) शासक वर्ग की शक्ति का आर्थिक औचित्य।
(B) नियंत्रण बनाए रखने के लिए अभिजन द्वारा उपयोग की जाने वाली सैन्य रणनीति।
(C) चुनावी प्रणाली जो अभिजन के प्रभुत्व को सुनिश्चित करती है।
(D) कानूनी और नैतिक सिद्धांत जो शासक वर्ग की शक्ति को न्यायोचित ठहराते हैं।

28. तुलनात्मक राजनीति के पारंपरिक दृष्टिकोण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह विधायिका और कार्यपालिका जैसी औपचारिक संस्थाओं के अध्ययन पर अत्यधिक केंद्रित था।
2. यह मुख्य रूप से सरकार के 'सर्वोत्तम' रूप को निर्धारित करने से संबंधित था।
3. इसने मुख्य रूप से गैर-पश्चिमी देशों के अनुभवों से अपने साक्ष्य जुटाए।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3

29. 'शक्तियों के संलयन' की विशेषता वाली कार्यपालिका और विधायिका के बीच अंतर्संबंध किस प्रणाली की पहचान है?
(A) राष्ट्रपति प्रणाली
(B) सत्तावादी प्रणाली
(C) संसदीय प्रणाली
(D) संघीय प्रणाली

30. राजनीतिक विकास के विश्लेषण में, 'वैधता का संकट' तब होता है जब:
(A) जनसंख्या शासन करने के लिए सरकार के उचित अधिकार पर सवाल उठाती है।
(B) सरकार अपने नागरिकों को बुनियादी सेवाएं प्रदान करने में असमर्थ होती है।
(C) विभिन्न जातीय या क्षेत्रीय समूह एक सामान्य राष्ट्रीय पहचान बनाने में विफल रहते हैं।
(D) सरकार अधिक जनभागीदारी की मांगों का प्रबंधन नहीं कर पाती है।

31. तुलनात्मक राजनीति में कार्ल डॉयच का योगदान किस क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण है?
(A) राजनीतिक संस्कृति
(B) अभिजन सिद्धांत
(C) संरचनात्मक प्रकार्यवाद
(D) राजनीतिक संचार

Click Here to Buy book on Amazon

32. यह विचार कि आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य क्षेत्रों के नेताओं से बना एक 'शक्ति अभिजन' आधुनिक औद्योगिक समाज पर हावी है, किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था?
(A) रॉबर्ट डहल
(B) सी. राइट मिल्स
(C) जोसेफ शुम्पेटर
(D) रॉबर्ट मिचल्स

33. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।
अभिकथन (A): न्यायपालिका की न्यायिक समीक्षा की शक्ति विधायिका और कार्यपालिका पर एक महत्वपूर्ण नियंत्रण के रूप में कार्य करती है।
कारण (R): न्यायिक समीक्षा अदालतों की वह शक्ति है जिसके द्वारा वे कानूनों और कार्यकारी कार्यों को असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं।
(A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(D) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

34. एकसदनीय विधायिका वह है जो:
(A) एक ही सदन या कक्ष से बनी होती है।
(B) जिसमें दो सदन या कक्ष होते हैं।
(C) कार्यकारी शाखा के अधीन होती है।
(D) केवल संघीय प्रणालियों में पाई जाती है।

35. निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक व्यवस्था में 'हित समूहन' का सबसे अच्छा उदाहरण है?
(A) सरकार की नीति की आलोचना करने वाला समाचार पत्र का संपादकीय।
(B) अपने सदस्यों के लिए उच्च वेतन की मांग करने वाला श्रमिक संघ।
(C) एक राजनीतिक दल जो विभिन्न समूहों की मांगों को समन्वित करने वाला एक मंच विकसित करता है।
(D) एक परिवार जो अपने बच्चों को राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना सिखाता है।

36. निम्नलिखित शास्त्रीय अभिजन सिद्धांतकारों को उनके प्रमुख कार्यों के कालानुक्रमिक प्रकाशन के आधार पर व्यवस्थित करें:
1. गेटानो मोस्का
2. विल्फ्रेडो पेरेटो
3. रॉबर्ट मिचल्स
(A) 1, 3, 2
(B) 2, 1, 3
(C) 1, 2, 3
(D) 3, 1, 2

37. व्यवस्था विश्लेषण मॉडल में, 'फीडबैक' वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा:
(A) व्यवस्था मांगों को निर्गत में परिवर्तित करती है।
(B) पर्यावरण राजनीतिक व्यवस्था पर दबाव डालता है।
(C) व्यवस्था के निष्पादन के बारे में जानकारी वापस उसे प्रेषित की जाती है।
(D) सरकार आधिकारिक तौर पर मूल्यों का आवंटन करती है।

38. तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन मुख्य रूप से संबंधित है:
(A) अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में संप्रभु राज्यों के बीच संबंध।
(B) राजनीतिक प्रणालियों के बीच और उनके भीतर समानताएं और अंतर।
(C) एक आदर्श राज्य की दार्शनिक नींव।
(D) अंतर्राष्ट्रीय कानून का ऐतिहासिक विकास।

39. राजनीतिक आधुनिकीकरण के संबंध में एक केंद्रीय तर्क यह है कि:
(A) आर्थिक विकास स्वतः ही राजनीतिक स्थिरता की ओर मार्ग प्रशस्त करता है।
(B) लोकतंत्र सभी सामाजिक प्रक्रियाओं के अपरिहार्य और अंतिम पड़ाव के रूप में कार्य करता है।
(C) निरंतर सामाजिक प्रगति सुनिश्चित करने के लिए पारंपरिक संस्थाओं को समाप्त किया जाना चाहिए।
(D) यदि संस्थागत विकास अपर्याप्त है, तो आधुनिकीकरण से राजनीतिक पतन होता है।

40. नीचे दो कथन दिए गए हैं:
कथन I: तुलनात्मक राजनीति में पारंपरिक दृष्टिकोण की अक्सर 'यूरोप-केंद्रित' होने के लिए आलोचना की जाती थी।
कथन II: पारंपरिक दृष्टिकोण मुख्य रूप से यूरोप और उत्तरी अमेरिका में सरकारों की औपचारिक-कानूनी संरचनाओं पर केंद्रित था।
(A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं।
(C) कथन I सत्य है, लेकिन कथन II असत्य है।
(D) कथन I असत्य है, लेकिन कथन II सत्य है।

41. द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उभरी आधुनिक तुलनात्मक राजनीति की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है?
(A) अधिक विश्लेषणात्मक होने और कम वर्णनात्मक होने की ओर बदलाव।
(B) सिद्धांतों और सामान्यीकरणों को विकसित करने का प्रयास।
(C) गैर-पश्चिमी देशों को शामिल करने के लिए दायरे का विस्तार।
(D) विशेष रूप से औपचारिक सरकारी संस्थानों पर ध्यान केंद्रित करना।

42. राजनीतिक संस्कृति के वर्गीकरण में, एक 'संकीर्ण' संस्कृति वह है जहाँ:

NODIA

(A) नागरिक राजनीतिक प्रक्रिया में अत्यधिक संलग्न होते हैं।
(B) नागरिकों को राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बहुत कम या बिल्कुल जानकारी नहीं होती है।
(C) नागरिक सरकार के प्रति जागरूक हैं लेकिन निष्क्रिय हैं।
(D) नागरिकों में सहभागी और प्रजाभावी दोनों अभिवृत्तियाँ होती हैं।

43. अवधारणाओं के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा अपने प्रतिपादक के साथ गलत सुमेलित है?
(A) शक्ति अभिजन - सी. राइट मिल्स
(B) अल्पतंत्र का लौह नियम - रॉबर्ट मिचल्स
(C) अभिजन का संचलन - गेटानो मोस्का
(D) व्यवस्था विश्लेषण - डेविड ईस्टन

44. संसदीय प्रणाली में सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, जबकि राष्ट्राध्यक्ष अक्सर होता है:
(A) कार्यकारी शक्तियों के साथ एक अलग, प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति।
(B) उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश।
(C) संसद के निचले सदन के अध्यक्ष।
(D) एक औपचारिक सम्राट या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति।

45. मार्क्सवादी दृष्टिकोण समाज की 'अधिसंरचना' को किसके द्वारा निर्धारित मानता है?
(A) जनसंख्या के बहुमत की इच्छा।
(B) महान ऐतिहासिक नेताओं के कार्य।
(C) 'आधार', जो उत्पादन की विधि है।
(D) अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की अराजक प्रकृति।

46. 'लोकतंत्र के अभिजनवादी सिद्धांत' का केंद्रीय विचार क्या है?
(A) सच्चा लोकतंत्र लोगों द्वारा प्रत्यक्ष शासन है।
(B) लोकतंत्र केवल एक सत्तारूढ़ अभिजन को चुनने की एक प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया है।
(C) सभी नागरिकों के पास नीति को प्रभावित करने का समान और प्रभावी अवसर होता है।
(D) एक एकल, एकीकृत शक्ति अभिजन लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधित करता है।

47. यह विचार कि राजनीतिक विकास सचेत रूप से खोजी गई समस्या-समाधान क्षमता का अर्जन है, किसके कार्य का केंद्र है?
(A) लुसियन पाई
(B) सैमुअल हंटिंगटन
(C) डेविड ईस्टन
(D) गैब्रियल आलमंड और बिंघम पॉवेल

48. सूची I को सूची II के साथ सुमेलित करें।
सूची I: (आगत कार्य)
P. हित प्रकटीकरण
Q. हित समूहन
R. राजनीतिक समाजीकरण
S. राजनीतिक संचार
सूची II: (विवरण)
1. विभिन्न मांगों को एक सुसंगत नीति कार्यक्रम में जोड़ना।
2. राजनीतिक व्यवस्था के समक्ष आवश्यकताओं और मांगों को व्यक्त करना।
3. पूरे समाज में राजनीतिक जानकारी प्रसारित करना।
4. पीढ़ियों तक राजनीतिक मूल्यों और मानदंडों को प्रेषित करना।
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:
(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-2, Q-1, R-4, S-3
(C) P-4, Q-3, R-2, S-1
(D) P-2, Q-4, R-1, S-3

49. राष्ट्रपति प्रणाली और संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका के बीच मुख्य अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है?
(A) राष्ट्रपति कार्यपालिका को विधायिका द्वारा चुना जाता है, जबकि संसदीय कार्यपालिका सीधे जनता द्वारा चुनी जाती है।
(B) राष्ट्रपति कार्यपालिका राष्ट्राध्यक्ष और सरकार के प्रमुख की भूमिकाओं को जोड़ती है, जबकि संसदीय प्रणाली में वे हमेशा अलग होते हैं।
(C) राष्ट्रपति कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित होता है, जबकि संसदीय कार्यपालिका का कार्यकाल विधायिका के विश्वास पर निर्भर करता है।
(D) राष्ट्रपति कार्यपालिका हमेशा संसदीय कार्यपालिका से कमजोर होती है।

50. निम्नलिखित में से कौन तुलनात्मक राजनीति के 'दायरे' का सबसे अच्छा वर्णन करता है?
(A) इसमें राज्यों के भीतर राजनीति और सरकार के सभी पहलू शामिल हैं।
(B) यह लोकतांत्रिक शासन के अध्ययन तक सीमित है।
(C) यह लिखित संविधानों के विश्लेषण तक ही सीमित है।
(D) यह केवल विभिन्न देशों की चुनावी प्रक्रियाओं पर केंद्रित है।

51. राजनीति के व्यवस्था दृष्टिकोण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह राजनीतिक व्यवस्था को एक पर्यावरण में विद्यमान मानता है।
2. यह राजनीति को "मूल्यों के आधिकारिक आवंटन" के रूप में अवधारणाबद्ध करता है।
3. यह संस्थानों और संरचनाओं की भूमिका को पूरी तरह से अनदेखा करता है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं?
(A) केवल 1 और 3
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 2

Downloaded from www.pdf.tube

(D) 1, 2 और 3

52. यह विचार कि राजनीतिक विकास में पहचान, वैधता और भागीदारी के संकटों का प्रबंधन शामिल है, व्यवस्थित रूप से किसके द्वारा विकसित किया गया था?
(A) कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स।
(B) तुलनात्मक राजनीति समिति, विशेष रूप से लुसियन पाई।
(C) डेविड ईस्टन।
(D) रॉबर्ट डहल।

53. विल्फ्रेडो पेरेटो की अभिजन की अवधारणा शासी अभिजन के किस वर्गीकरण पर आधारित है?
(A) शासक वर्ग और जनसमूह।
(B) शक्ति अभिजन और जनता।
(C) 'शेर' और 'लोमड़ी'।
(D) राजनीतिक वर्ग और गैर-राजनीतिक वर्ग।

54. वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जनसंचार माध्यम सार्वजनिक प्राथमिकताओं को प्रभावित करते हैं, किसका एक पहलू है?
(A) राजनीतिक समाजीकरण
(B) हित प्रकटीकरण
(C) राजनीतिक भर्ती
(D) राजनीतिक संचार

55. 'न्यायिक स्वतंत्रता' की अवधारणा का तात्पर्य है कि:
(A) न्यायाधीशों को सरकार की अन्य शाखाओं के राजनीतिक दबाव से मुक्त होना चाहिए।
(B) न्यायाधीशों का चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाता है।
(C) न्यायपालिका के पास नए कानून बनाने का अधिकार है।
(D) न्यायाधीशों को अपने निर्णयों के लिए कारण बताने की आवश्यकता नहीं है।

56. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।
अभिकथन (A): संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण पारंपरिक संस्थागत दृष्टिकोण की तुलना में एक महत्वपूर्ण प्रगति थी।
कारण (R): इसने उन कार्यों की जांच करके विभिन्न प्रकार की राजनीतिक प्रणालियों की तुलना करने की अनुमति दी जो सभी प्रणालियाँ संपन्न करती हैं।
(A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(D) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

57. कौन सा कथन 'अर्ध-राष्ट्रपति' प्रणाली का सटीक वर्णन करता है?
(A) यह एक शक्तिशाली प्रधानमंत्री और पूरी तरह से औपचारिक राष्ट्रपति वाली प्रणाली है।
(B) यह मानक संसदीय प्रणाली के लिए एक अन्य शब्द है।
(C) इसमें महत्वपूर्ण शक्तियों के साथ सीधे निर्वाचित राष्ट्रपति और संसद के प्रति उत्तरदायी प्रधानमंत्री दोनों होते हैं।
(D) यह एक ऐसी प्रणाली है जहाँ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हमेशा एक ही राजनीतिक दल से होते हैं।

NOIDA

58. "नागरिक संस्कृति" की अवधारणा को इस रूप में परिभाषित किया गया है:
(A) सहभागी, प्रजाभावी और संकीर्ण संस्कृतियों का मिश्रण, जिसे लोकतंत्र के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है।
(B) एक शुद्ध सहभागी राजनीतिक संस्कृति।
(C) केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में पाई जाने वाली राजनीतिक संस्कृति।
(D) एक ऐसी संस्कृति जहाँ नागरिक राजनीति के प्रति पूरी तरह उदासीन होते हैं।

59. तुलनात्मक राजनीति में 'व्यवहारवादी' दृष्टिकोण किसके अध्ययन पर जोर देता है?
(A) औपचारिक संवैधानिक दस्तावेज और कानून।
(B) राजनीतिक संस्थाओं का इतिहास।
(C) राज्य की शक्ति का दार्शनिक औचित्य।
(D) राजनीतिक अभिनेताओं, जैसे मतदाताओं और विधायकों का वास्तविक व्यवहार।

60. तुलनात्मक राजनीति के बौद्धिक इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करें:
1. "द सिविक कल्चर" का प्रकाशन।
2. पारंपरिक, औपचारिक-कानूनी दृष्टिकोण का उदय।
3. व्यवस्था दृष्टिकोण का प्रतिपादन।
4. "द पावर एलीट" का प्रकाशन।
(A) 2, 4, 3, 1
(B) 2, 3, 4, 1
(C) 1, 2, 4, 3
(D) 3, 2, 1, 4

61. निम्नलिखित में से कौन सा राजनीति के प्रति मार्क्सवादी दृष्टिकोण का मूल सिद्धांत नहीं है?
(A) इतिहास में वर्ग संघर्ष की केंद्रीयता।
(B) आर्थिक आधार राजनीतिक अधिसंरचना को निर्धारित करता है।
(C) राज्य वर्गों के बीच एक तटस्थ मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है।
(D) पूंजीवाद में आंतरिक विरोधाभास हैं जो इसके पतन का कारण बनेंगे।

62. 'विधायिकाओं का पतन' का सिद्धांत बताता है कि आधुनिक राज्यों में:
(A) विधायिकाएं कार्यपालिका की तुलना में अधिक शक्तिशाली हो गई हैं।
(B) विश्व स्तर पर विधायी निकायों की संख्या कम हो रही है।

(C) नागरिकों ने विधायी प्रतिनिधित्व में पूर्ण विश्वास खो दिया है।
(D) कार्यपालिका और नौकरशाही की तुलना में विधायिकाओं की शक्ति कम हो गई है।

63. राजनीतिक आधुनिकीकरण सिद्धांत की उसके प्रारंभिक रूप में अक्सर इस कारण से आलोचना की गई थी:
(A) इसके सजाति-केंद्रित होने और पश्चिम पर आधारित विकास के एकरेखीय पथ को मानने के कारण।
(B) प्रत्येक देश के अद्वितीय पहलुओं पर बहुत अधिक केंद्रित होने के कारण।
(C) राजनीतिक परिवर्तन में आर्थिक कारकों की भूमिका को अनदेखा करने के कारण।
(D) सैन्य शक्ति के महत्व पर अत्यधिक जोर देने के कारण।

64. सरकार की 'कार्यकारी' शाखा की प्राथमिक भूमिका क्या है?
(A) कानून बनाना।
(B) कानूनों को लागू करना और उनका पालन कराना।
(C) कानूनों की व्याख्या करना।
(D) उप-राष्ट्रीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करना।

65. नीचे दो कथन दिए गए हैं:
कथन I: लोकतंत्र का अभिजनवादी सिद्धांत तर्क देता है कि अल्पसंख्यक द्वारा शासन सभी बड़े समाजों की एक अपरिहार्य विशेषता है।
कथन II: इसके विपरीत, बहुलवादी सिद्धांत का तर्क है कि शक्ति प्रतिस्पर्धी समूहों के बीच व्यापक रूप से वितरित है।
(A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं।
(C) कथन I सत्य है, लेकिन कथन II असत्य है।
(D) कथन I असत्य है, लेकिन कथन II सत्य है।

66. निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक विधायिका का वैध कार्य नहीं माना जाता है?
(A) कानून बनाना
(B) आपराधिक मामलों का अधिनिर्णयन
(C) कार्यपालिका की निगरानी
(D) निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व

67. 'राजनीतिक समाजीकरण' की अवधारणा को सबसे अच्छी तरह इस प्रकार परिभाषित किया गया है:
(A) किसी राजनीतिक दल में शामिल होने की प्रक्रिया।
(B) चुनाव के दौरान उम्मीदवारों द्वारा की जाने वाली अभियान गतिविधियाँ।
(C) विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान का औपचारिक अध्ययन।
(D) राजनीतिक अभिवृत्तियों और व्यवहारों को सीखने और प्राप्त करने की आजीवन प्रक्रिया।

68. अभिजन सिद्धांतों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. पेरेटो ने अभिजनों को 'शेर' और 'लोमड़ी' के रूप में वर्गीकृत किया।
2. मोस्का ने सत्तारूढ़ अल्पसंख्यक की संगठनात्मक श्रेष्ठता पर जोर दिया।
3. मिचल्स ने 'अल्पतंत्र का लौह नियम' प्रस्तावित किया।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3

69. राजनीति के व्यवस्था मॉडल में, 'रूपांतरण प्रक्रिया' क्या है?
(A) अधिकारियों तक सूचना का वापस जाना।
(B) अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण से बाहरी दबाव।
(C) वे संस्थाएं और प्रक्रियाएं जो आगत को निर्गत में बदलती हैं।
(D) हित समूहों द्वारा मांगों का प्रकटीकरण।

70. तुलनात्मक राजनीति के पारंपरिक दृष्टिकोण की प्राथमिक कमजोरी थी:
(A) विश्लेषणात्मक और व्याख्यात्मक होने के बजाय वर्णनात्मक और औपचारिक होने की प्रवृत्ति।
(B) सांख्यिकीय विश्लेषण पर अत्यधिक जोर देना।
(C) केवल विकासशील देशों की राजनीति पर ध्यान केंद्रित करना।
(D) राजनीतिक विश्लेषण में ऐतिहासिक संदर्भ को अस्वीकार करना।

71. सूची I को सूची II के साथ सुमेलित करें।
सूची I: (लेखक)
P. सैमुअल पी. हंटिंगटन
Q. गैब्रियल आलमंड और सिडनी वर्बा
R. सी. राइट मिल्स
S. जोसेफ शुम्पेटर
सूची II: (प्रमुख अवधारणा/कार्य)
1. द सिविक कल्चर
2. पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज
3. द पावर एलीट
4. कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:
(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-2, Q-1, R-3, S-4
(C) P-2, Q-3, R-1, S-4
(D) P-3, Q-1, R-4, S-2

72. राजनीतिक विश्लेषण में 'नियम अधिनिर्णयन' का कार्य सरकार के किस अंग की भूमिका के अनुरूप है?
(A) विधायिका
(B) न्यायपालिका
(C) कार्यपालिका
(D) नौकरशाही

Click Here to Buy book on Amazon

73. राजनीति विज्ञान में 'उत्तर-व्यवहारवादी' आंदोलन ने किसके लिए तर्क दिया?
(A) विशुद्ध रूप से वर्णनात्मक, संस्थागत अध्ययन की ओर वापसी।
(B) वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोग की परवाह किए बिना अमूर्त मॉडल-निर्माण पर अधिक ध्यान।
(C) 'प्रासंगिकता' और 'कार्रवाई' पर जोर, शोध को सामाजिक समस्याओं से जोड़ना।
(D) राजनीतिक जांच में वैज्ञानिक तरीकों का पूरी तरह से त्याग।

74. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।
अभिकथन (A): सरकार की संघीय प्रणाली में, द्विसदनीय विधायिका सामान्य है।
कारण (R): संघीय प्रणाली में दूसरा सदन राष्ट्रीय विधान में घटक इकाइयों की आवाज सुनिश्चित करता है।
(A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(D) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

75. मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अनुसार, पूंजीवादी समाज में राज्य का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?
(A) बुर्जुआ वर्ग की संपत्ति और हितों की रक्षा करना।
(B) सभी नागरिकों के लिए सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना।
(C) वर्ग संघर्ष में एक तटस्थ रेफरी के रूप में कार्य करना।
(D) वर्गविहीन समाज की ओर संक्रमण को सुगम बनाना।

76. "कौन क्या, कब और कैसे प्राप्त करता है" राजनीति की एक प्रसिद्ध परिभाषा है जिसका श्रेय दिया जाता है:
(A) डेविड ईस्टन
(B) हेरोल्ड लासवेल
(C) गैब्रियल आलमंड
(D) कार्ल डॉयच

77. निम्नलिखित में से कौन सा संकट पूरे क्षेत्र में केंद्र सरकार की उपस्थिति स्थापित करने की समस्या से संबंधित है?
(A) पहचान का संकट
(B) पैठ का संकट
(C) वैधता का संकट
(D) वितरण का संकट

78. संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार के अंगों के बीच संबंध का सबसे सटीक वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा है?
(A) नियंत्रण और संतुलन के साथ शक्ति पृथक्करण की प्रणाली।
(B) कार्यपालिका और विधायिका के बीच शक्तियों का संलयन।
(C) अन्य सभी शाखाओं पर विधायिका की सर्वोच्चता।
(D) दोहरी कार्यपालिका वाली एक अर्ध-राष्ट्रपति प्रणाली।

79. राजनीतिक मानदंड और मूल्य एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को कैसे हस्तांतरित होते हैं, इसका अध्ययन किसका मूल है?
(A) राजनीतिक संचार
(B) राजनीतिक आधुनिकीकरण
(C) राजनीतिक समाजीकरण
(D) राजनीतिक विकास

80. रॉबर्ट मिचल्स का 'अल्पतंत्र का लौह नियम' उनके किस अध्ययन पर आधारित था?
(A) ब्रिटिश संसद
(B) जर्मन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी
(C) अमेरिकी 'शक्ति अभिजन'
(D) प्राचीन यूनानी नगर-राज्य

81. सामान्य व्यवस्था मॉडल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक व्यवस्था का 'निर्गत' नहीं है?
(A) कानून
(B) न्यायिक निर्णय
(C) सार्वजनिक नीतियां
(D) जन समर्थन

82. संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण का प्राथमिक लक्ष्य यह समझाना है:
(A) राजनीतिक प्रणालियाँ खुद को कैसे बनाए रखती हैं और अनुकूलित करती हैं।
(B) आधुनिक राज्य का ऐतिहासिक विकास।
(C) लोकतंत्र का दार्शनिक औचित्य।
(D) पूंजीवाद के भीतर अंतर्निहित विरोधाभास।

83. कार्यपालिका के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संसदीय प्रणाली में, कार्यपालिका विधायिका की सदस्य भी होती है।
2. राष्ट्रपति प्रणाली में, कार्यपालिका का कार्यकाल विधायी विश्वास पर निर्भर नहीं होता है।
3. 'राष्ट्राध्यक्ष' और 'सरकार के प्रमुख' हमेशा एक ही व्यक्ति होते हैं।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3

84. 'राजनीतिक अभिजन' की अवधारणा मौलिक रूप से क्या सुझाव देती है?
(A) राजनीति में सभी नागरिकों की समान बात सुनी जाती है।
(B) आर्थिक शक्ति राजनीतिक शक्ति का एकमात्र निर्धारक है।

Downloaded from www.pdf.tube

(C) अभिजनों को हमेशा लोकतांत्रिक चुनावों के माध्यम से चुना जाता है।
(D) राजनीतिक शक्ति एक छोटे अल्पसंख्यक के पास होती है।

85. निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक आधुनिकीकरण सिद्धांत के अनुरूप कार्य-कारण संबंध का प्रतिनिधित्व करता है?
(A) कारण: मजबूत लोकतांत्रिक संस्थाएं। प्रभाव: आर्थिक अल्पविकास।
(B) कारण: व्यापक राजनीतिक भागीदारी। प्रभाव: सरकारी क्षमता में गिरावट।
(C) कारण: साक्षरता और संचार माध्यमों के प्रसार का उच्च स्तर। प्रभाव: राजनीतिक भागीदारी में वृद्धि।
(D) कारण: पारंपरिक सामाजिक संरचनाएं। प्रभाव: तीव्र राजनीतिक आधुनिकीकरण।

86. किस ऐतिहासिक अध्ययन के प्रकाशन के बाद तुलनात्मक राजनीति में 'राजनीतिक संस्कृति' की अवधारणा को प्रमुखता मिली?
(A) "द पॉलिटिकल सिस्टम"
(B) "द सिविक कल्चर"
(C) "पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज"
(D) "द रूलिंग क्लास"

87. तुलनात्मक राजनीति के 'पारंपरिक दृष्टिकोण' की परिभाषित विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है?
(A) राजनीतिक व्यवहार और अभिवृत्तियों पर ध्यान केंद्रित करना।
(B) सांख्यिकीय विधियों और सर्वेक्षण अनुसंधान का उपयोग।
(C) विकासशील देशों पर जोर।
(D) एक आदर्शात्मक और कानूनी-संस्थागत केंद्र बिंदु।

88. राजनीतिक व्यवस्था के निम्नलिखित कार्यों को आगत और निर्गत श्रेणियों में व्यवस्थित करें:
1. हित प्रकटीकरण
2. नियम निर्माण
3. राजनीतिक समाजीकरण
4. नियम अधिनिर्णयन
(A) आगत: 1, 3; निर्गत: 2, 4
(B) आगत: 1, 2; निर्गत: 3, 4
(C) आगत: 3, 4; निर्गत: 1, 2
(D) आगत: 2, 4; निर्गत: 1, 3

89. राजनीति के प्रति व्यवस्था दृष्टिकोण की एक प्रमुख मान्यता यह है कि:
(A) राजनीतिक व्यवस्था एक पृथक इकाई है।
(B) राजनीति का अध्ययन केवल ऐतिहासिक दृष्टिकोण से ही किया जा सकता है।
(C) राजनीतिक व्यवस्था अंत:क्रियाओं का एक समूह है जो अपने पर्यावरण से अलग पहचाने जाने योग्य है।
(D) आर्थिक संरचना राजनीतिक जीवन की एकमात्र निर्धारक है।

90. तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य में, 'न्यायिक समीक्षा' की शक्ति सामान्यत: किस देश में सबसे मजबूत मानी जाती है?
(A) संयुक्त राज्य अमेरिका
(B) यूनाइटेड किंगडम
(C) चीन
(D) स्विट्जरलैंड

91. नीचे दो कथन दिए गए हैं:
कथन I: आधुनिकीकरण की ओर बढ़ते समाजों में, सामाजिक गतिशीलता अक्सर संस्थागत विकास से आगे निकल जाती है।
कथन II: यह अंतराल राजनीतिक अस्थिरता और पतन की ओर ले जाता है।
(A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं।
(C) कथन I सत्य है, लेकिन कथन II असत्य है।
(D) कथन I असत्य है, लेकिन कथन II सत्य है।

92. संचार माध्यमों और सरकार से जनता तक राजनीतिक जानकारी का प्रेषण किसका विषय है?
(A) राजनीतिक अभिजन अध्ययन
(B) राजनीतिक संचार
(C) राजनीतिक विकास
(D) राजनीतिक भर्ती

93. यह सिद्धांत कि लोकतंत्र प्रतिस्पर्धा के माध्यम से नेताओं को चुनने की एक "प्रक्रियात्मक व्यवस्था" है, किसके साथ जुड़ा हुआ है?
(A) कार्ल मार्क्स
(B) जोसेफ शुम्पेटर
(C) सी. राइट मिल्स
(D) रॉबर्ट डहल

94. कार्यपालिकाओं के तुलनात्मक अध्ययन में निम्नलिखित में से किसका विश्लेषण नहीं किया जाएगा?
(A) राष्ट्राध्यक्ष और सरकार के प्रमुख के बीच संबंध।
(B) कार्यपालिका की कानून को वीटो करने की शक्ति।
(C) विधायिका के प्रति मंत्रिमंडल की जवाबदेही।
(D) न्यायिक नियुक्तियों की प्रक्रिया।

95. तुलनात्मक राजनीति के 'पारंपरिक' से 'आधुनिक' चरण में संक्रमण को किस लक्षण द्वारा चिन्हित किया गया था?
(A) आदर्शात्मक निर्धारण से आनुभविक व्याख्या की ओर बदलाव।
(B) शुद्ध विवरण के पक्ष में सिद्धांत का त्याग।
(C) केवल पश्चिमी यूरोपीय राज्यों पर ध्यान केंद्रित करना।
(D) संस्थाओं के अध्ययन का त्याग।

NODIA

96. सूची I को सूची II के साथ सुमेलित करें।
सूची I: (व्यवस्था सिद्धांत के शब्द)
P. आगत
Q. निर्गत
R. फीडबैक लूप
S. पर्यावरण
सूची II: (अर्थ)
1. राजनीतिक व्यवस्था की बाहरी स्थिति।
2. पर्यावरण से प्राप्त मांगें और समर्थन।
3. आधिकारिक निर्णय और नीतियां।
4. निर्गत से आगत की ओर सूचना मार्ग।
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:
(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-2, Q-3, R-4, S-1
(C) P-3, Q-4, R-1, S-2
(D) P-2, Q-1, R-4, S-3

97. 'राजनीतिक पतन' की अवधारणा किस विचारक के कार्य का केंद्र है?
(A) डेविड ईस्टन
(B) गैब्रियल आलमंड
(C) सैमुअल हंटिंगटन
(D) लुसियन पाई

98. कौन सा कथन शास्त्रीय अभिजन सिद्धांतकारों के दृष्टिकोण को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है?
(A) अल्पसंख्यक द्वारा शासन सामाजिक जीवन की एक अपरिहार्य विशेषता है।
(B) किसी अभिजन द्वारा शासन एक अस्थायी और अवांछनीय स्थिति है।
(C) सच्चा लोकतंत्र एक साध्य आदर्श है।
(D) अभिजन केवल सत्तावादी प्रणालियों में शासन करते हैं।

99. तुलनात्मक सरकार के संदर्भ में, 'नियंत्रण और संतुलन' का तात्पर्य है:
(A) सरकारी विभागों का वित्तीय ऑडिट।
(B) राष्ट्रीय बजट को संतुलित करने की प्रक्रिया।
(C) वह सिद्धांत कि सरकार की प्रत्येक शाखा दूसरों को सीमित कर सकती है।
(D) विधायिका में दूसरे सदन की आवश्यकता।

100. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।
अभिकथन (A): परिवार राजनीतिक समाजीकरण का एक शक्तिशाली अभिकर्ता है।
कारण (R): आधारभूत राजनीतिक अभिवृत्तियाँ अक्सर बचपन के दौरान माता-पिता से प्राप्त होती हैं।
(A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(D) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

101. मार्क्सवादी विश्लेषण में 'आधार', जो अधिसंरचना को आकार देता है, उसमें शामिल है:
(A) राज्य और उसका कानूनी तंत्र।
(B) उत्पादन की विधि।
(C) उत्पादन के संबंध और शक्तियां।
(D) सैन्य और पुलिस बल।

102. नागरिक संस्कृति ढांचे में सामान्यतः पहचाने जाने वाले राजनीतिक संस्कृति के प्रकारों में से निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है?
(A) संकीर्ण
(B) अभिजनवादी
(C) प्रजाभावी
(D) सहभागी

103. संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण के विरुद्ध की जाने वाली प्राथमिक आलोचना क्या है?
(A) यह गैर-पश्चिमी प्रणालियों का अध्ययन करने में असमर्थ है।
(B) यह अत्यधिक ऐतिहासिक और वर्णनात्मक है।
(C) यह राजनीति में व्यक्तियों की भूमिका को पूरी तरह से अनदेखा करता है।
(D) इसमें व्यवस्था के अनुरक्षण के प्रति एक रूढ़िवादी झुकाव है।

104. नीचे दो कथन दिए गए हैं:
कथन I: विधायिका का प्राथमिक कार्य नियम निर्माण है।
कथन II: कार्यपालिका का प्राथमिक कार्य नियम अनुप्रयोग है।
(A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं।
(C) कथन I सत्य है, लेकिन कथन II असत्य है।
(D) कथन I असत्य है, लेकिन कथन II सत्य है।

105. "वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक पारंपरिक समाज आधुनिक समाज की विशेषताएं प्राप्त करता है" किसे परिभाषित करती है?
(A) राजनीतिक समाजीकरण
(B) राजनीतिक विकास
(C) राजनीतिक आधुनिकीकरण
(D) राजनीतिक एकीकरण

106. पारंपरिक और व्यवहारवादी दृष्टिकोणों के बीच एक मुख्य अंतर यह है कि व्यवहारवादी दृष्टिकोण:
(A) मूल्य-मुक्त और आनुभविक होने का प्रयास करता है।
(B) मुख्य रूप से आदर्शात्मक है।
(C) इस पर ध्यान केंद्रित करता है कि सरकारों को क्या 'करना चाहिए'।
(D) संविधानों के अध्ययन तक सीमित है।

Click Here to Buy book on Amazon

107. 'छाया मंत्रिमंडल' का अस्तित्व किस राजनीतिक व्यवस्था की एक विशिष्ट विशेषता है?
(A) अमेरिकी राष्ट्रपति प्रणाली
(B) फ्रांसीसी अर्ध-राष्ट्रपति प्रणाली
(C) चीनी एक-दलीय प्रणाली
(D) ब्रिटिश संसदीय प्रणाली

108. 'अभिजनों का संचलन' की अवधारणा, जहाँ एक अभिजन समूह का स्थान दूसरा ले लेता है, किसके द्वारा विस्तृत की गई थी?
(A) रॉबर्ट मिचल्स
(B) विल्फ्रेडो पेरेटो
(C) सी. राइट मिल्स
(D) गेटानो मोस्का

109. निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक आधुनिकीकरण की एक विशिष्ट विशेषता नहीं है?
(A) प्राधिकार का युक्तिकरण
(B) राजनीतिक भागीदारी में वृद्धि
(C) पारंपरिक निष्ठाओं का सुदृढ़ीकरण
(D) संरचनात्मक विभेदीकरण

110. लुसियन पाई द्वारा पहचाने गए राजनीतिक विकास के 'संकटों' को व्यवस्थित करें:
1. भागीदारी
2. पहचान
3. वैधता
4. वितरण
(A) 2, 3, 1, 4
(B) 1, 2, 3, 4
(C) 4, 3, 2, 1
(D) 3, 1, 4, 2

111. कौन सा दृष्टिकोण वर्ग संघर्ष और राज्य को वर्ग प्रभुत्व के एक साधन के रूप में केंद्र में रखकर राजनीति का विश्लेषण करता है?
(A) व्यवस्था दृष्टिकोण
(B) संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण
(C) पारंपरिक दृष्टिकोण
(D) मार्क्सवादी दृष्टिकोण

112. विधायी कार्यों की संवैधानिकता निर्धारित करने की अदालतों की क्षमता को किस रूप में जाना जाता है?
(A) न्यायिक सक्रियता
(B) न्यायिक समीक्षा
(C) न्यायिक संयम
(D) न्यायिक संप्रभुता

113. तुलनात्मक पद्धति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह राजनीतिक प्रणालियों में समानताएं और अंतर पहचानने का प्रयास करती है।
2. इसका उद्देश्य राजनीति के बारे में सामान्यीकरण विकसित करना और उनका परीक्षण करना है।
3. यह एक वर्णनात्मक अनुशासन से एक विश्लेषणात्मक अनुशासन के रूप में विकसित हुई है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3

114. 'राजनीतिक संचार' शब्द विशेष रूप से किसे संदर्भित करता है?
(A) समाज के माध्यम से राजनीतिक रूप से प्रासंगिक जानकारी का प्रवाह।
(B) एक राजनीतिक दल के भीतर आंतरिक बहस।
(C) संसदीय बहसों में प्रयुक्त भाषा।
(D) राजनीतिक मूल्यों को सीखने की प्रक्रिया।

115. सी. राइट मिल्स की 'शक्ति अभिजन' की अवधारणा ने किन तीन क्षेत्रों के व्यक्तियों से बने एक समूह का वर्णन किया?
(A) शिक्षाविद, जनसंचार माध्यम और न्यायपालिका
(B) श्रमिक संघ, धार्मिक समूह और नागरिक समाज
(C) राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य
(D) संघीय, राज्य और स्थानीय सरकारें

116. सरकार के राष्ट्रपति स्वरूप की एक प्रमुख विशेषता है:
(A) कार्यपालिका विधायिका का भाग होती है।
(B) प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है।
(C) मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होता है।
(D) कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित होता है।

117. राजनीति के प्रणालीगत मॉडल के अनुसार, राजनीतिक व्यवस्था के "पर्यावरण" में शामिल हैं:
(A) केवल घरेलू सामाजिक और आर्थिक स्थितियां।
(B) व्यवस्था को प्रभावित करने वाले अंतः-सामाजिक और बाह्य-सामाजिक पहलू।
(C) केवल अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था।
(D) वे संस्थाएं जो आगत को निर्गत में बदलती हैं।

118. यह तर्क कि "जो संगठन कहता है, वह अल्पतंत्र कहता है" किसका सार है?
(A) अल्पतंत्र का लौह नियम।
(B) अभिजन संचलन का सिद्धांत।
(C) राजनीतिक सूत्र की अवधारणा।
(D) प्रतिस्पर्धी अभिजनवाद का सिद्धांत।

119. सूची I को सूची II के साथ सुमेलित करें।
सूची I: (विशेषता)
P. संसदीय संप्रभुता

NODIA

Q. शक्तियों का सख्त पृथक्करण
R. अर्ध-राष्ट्रपतिवाद
S. रचनात्मक अविश्वास प्रस्ताव

सूची II: (उदाहरण)
1. संयुक्त राज्य अमेरिका
2. यूनाइटेड किंगडम
3. जर्मनी
4. फ्रांस

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:
(A) P-2, Q-1, R-4, S-3
(B) P-1, Q-2, R-3, S-4
(C) P-2, Q-4, R-1, S-3
(D) P-3, Q-1, R-4, S-2

120. राजनीतिक संस्कृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
(A) यह राजनीति के प्रति एक व्यक्तिपरक, मनोवैज्ञानिक अभिवृत्ति है।
(B) इसे सर्वेक्षण अनुसंधान के माध्यम से मापा जा सकता है।
(C) यह राजनीतिक व्यवस्था की स्थिरता को प्रभावित करती है।
(D) यह स्थिर होती है और समय के साथ बदलती नहीं है।

121. द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तुलनात्मक राजनीति का विस्तार मुख्य रूप से किसके द्वारा प्रेरित था?
(A) शीत युद्ध का अंत।
(B) व्यवहारवादी आंदोलन का पतन।
(C) एशिया और अफ्रीका में नए स्वतंत्र राज्यों का उदय।
(D) आर्थिक वैश्वीकरण का उदय।

122. दो सदनों वाली विधायिका को इस प्रकार वर्णित किया जाता है:
(A) द्विसदनीय
(B) एकसदनीय
(C) बहुसदनीय
(D) गैर-सदनीय

123. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।
अभिकथन (A): मार्क्सवादी दृष्टिकोण की अक्सर आर्थिक नियतिवाद के लिए आलोचना की जाती है।
कारण (R): यह राजनीतिक अधिसंरचना को आर्थिक आधार द्वारा निर्धारित मानने की प्रवृत्ति रखता है।
(A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(D) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

124. 'हित प्रकटीकरण' किसका कार्य है?
(A) मांगों को नीति में परिवर्तित करना।
(B) सरकार के समक्ष मांगों और जरूरतों को व्यक्त करना।
(C) विशिष्ट मामलों पर कानून लागू करना।
(D) युवाओं को राजनीतिक मूल्य सिखाना।

125. लोकतंत्र का अभिजनवादी सिद्धांत मौलिक रूप से किस शास्त्रीय लोकतांत्रिक विचार को चुनौती देता है?
(A) लिखित संविधान का महत्व।
(B) एक मजबूत सेना की आवश्यकता।
(C) 'जनता द्वारा शासन' का सिद्धांत।
(D) मुक्त बाजार पूंजीवाद का मूल्य।

126. राजनीतिक विकास के संदर्भ में, 'वितरण संकट' का तात्पर्य है:
(A) धन, वस्तुओं और सेवाओं के आधिकारिक आवंटन के संबंध में संघर्ष।
(B) क्षेत्र पर प्रभावी प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित करने में सरकार की अक्षमता।
(C) इस बात पर असहमति कि किन समूहों या व्यक्तियों के पास शासन करने का अधिकार है।
(D) विस्तारित जन भागीदारी के लिए नई और तीव्र मांगों का उदय।

127. निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक समाजीकरण के अभिकर्ता का सबसे अच्छा उदाहरण है?
(A) न्यायालय का निर्णय
(B) एक कानून
(C) सरकारी बजट
(D) विद्यालय का नागरिक शास्त्र पाठ्यक्रम

128. तुलनात्मक राजनीति में, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच अंतर्संबंधों का अध्ययन किसके अंतर्गत आता है?
(A) राजनीतिक संस्कृति
(B) राजनीतिक व्यवहार
(C) संस्थागत ढांचा
(D) अंतर्राष्ट्रीय संबंध

129. 'संकीर्ण-प्रजाभावी' या 'प्रजाभावी-सहभागी' शब्दों का उपयोग नागरिक संस्कृति ढांचे में किसे वर्णित करने के लिए किया जाएगा?
(A) शुद्ध राजनीतिक संस्कृतियाँ।
(B) सत्तावादी विचारधाराएँ।
(C) मिश्रित राजनीतिक संस्कृतियाँ।
(D) निष्क्रिय राजनीतिक व्यवस्थाएँ।

130. नीचे दो कथन दिए गए हैं:
कथन I: तुलनात्मक राजनीति के आधुनिक अनुशासन का उद्देश्य व्याख्यात्मक होना है।
कथन II: तुलनात्मक राजनीति का पारंपरिक अनुशासन वर्णनात्मक और आदर्शात्मक था।
(A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।

Downloaded from www.pdf.tube

(B) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं।
(C) कथन I सत्य है, लेकिन कथन II असत्य है।
(D) कथन I असत्य है, लेकिन कथन II सत्य है।

131. गेटानो मोस्का की 'राजनीतिक सूत्र' की अवधारणा किसे संदर्भित करती है?
(A) चुनाव जीतने के लिए एक गणितीय समीकरण।
(B) वह सिद्धांत या विचारधारा जो अभिजन के शासन को वैध बनाती है।
(C) राज्य की संवैधानिक संरचना।
(D) तख्तापलट की गुप्त योजना।

132. व्यवस्था दृष्टिकोण का एक प्रमुख योगदान क्या था?
(A) पर्यावरण के साथ प्रक्रिया और अंतःक्रिया पर जोर देने वाला एक गतिशील मॉडल प्रदान करना।
(B) औपचारिक-कानूनी संस्थाओं पर ध्यान वापस लाना।
(C) राजनीतिक परिवर्तन के इंजन के रूप में वर्ग संघर्ष के अध्ययन का समर्थन करना।
(D) पश्चिमी मॉडलों के आधार पर सरकार के आदर्श रूप को निर्धारित करना।

133. निम्नलिखित पर विचार करें:
एक सीधे निर्वाचित राष्ट्रपति, एक प्रधानमंत्री, और संसद के प्रति उत्तरदायी एक मंत्रिमंडल। यह किस प्रकार की व्यवस्था का वर्णन करता है?
(A) राष्ट्रपति प्रणाली
(B) संसदीय प्रणाली
(C) अर्ध-राष्ट्रपति प्रणाली
(D) परिसंघीय प्रणाली

134. राजनीतिक विकास के अध्ययन में निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न केंद्रीय है?
(A) अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में राज्य कैसे परस्पर क्रिया करते हैं?
(B) वे कौन सी राजनीतिक प्रक्रियाएं हैं जिनके माध्यम से समाज समय के साथ बदलते हैं?
(C) व्यक्ति और राज्य के बीच आदर्श संबंध क्या है?
(D) अंतर्राष्ट्रीय संधियों पर बातचीत कैसे की जाती है और उन्हें कैसे लागू किया जाता है?

135. अभिजन सिद्धांत में 'शेर' और 'लोमड़ी' की अवधारणा किसे संदर्भित करती है?
(A) दो अलग-अलग प्रकार के जनसमूह।
(B) अभिजन शासन की दो शैलियाँ, जो क्रमशः बल और चतुराई पर आधारित हैं।
(C) सरकार के सैन्य और नागरिक अंग।
(D) लोकतांत्रिक और सत्तावादी नेता।

136. तुलनात्मक राजनीति में 'व्यवहारवादी क्रांति' ने किस पर ध्यान केंद्रित करने का आह्वान किया?
(A) राज्य की दार्शनिक उत्पत्ति।
(B) संविधानों के औपचारिक-कानूनी पहलू।
(C) राजनीतिक संस्थाओं का ऐतिहासिक विकास।
(D) व्यक्तियों और समूहों का अवलोकन योग्य व्यवहार।

NODIA

137. संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक मॉडल में निम्नलिखित में से कौन सा 'आगत कार्य' नहीं है?
(A) हित प्रकटीकरण
(B) नियम निर्माण
(C) हित समूहन
(D) राजनीतिक समाजीकरण और भर्ती

138. 'राजनीतिक आधुनिकीकरण' और 'राजनीतिक विकास' के बीच मुख्य अंतर यह है कि:
(A) आधुनिकीकरण सामाजिक परिवर्तन है, जबकि विकास व्यवस्था की क्षमता है।
(B) विकास एक व्यापक प्रक्रिया है, जबकि आधुनिकीकरण एक संकीर्ण पहलू है।
(C) ये शब्द अनिवार्य रूप से समानार्थी हैं और इनमें कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है।
(D) आधुनिकीकरण पश्चिम पर लागू होता है, जबकि विकास पूर्व पर लागू होता है।

139. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।
अभिकथन (A): "अल्पतंत्र का लौह नियम" सुझाव देता है कि लोकतंत्र और बड़े पैमाने के संगठन असंगत हैं।
कारण (R): जैसे-जैसे संगठन बढ़ते हैं, शक्ति अनिवार्य रूप से कुछ नेताओं के हाथों में केंद्रित हो जाती है।
(A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(D) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

140. जब कोई अदालत संविधान की व्याख्या इस तरह करती है जिससे नए अधिकार या नीतियां बनती हैं, तो इसे कहा जाता है:
(A) न्यायिक सक्रियता
(B) न्यायिक संयम
(C) न्यायिक समीक्षा
(D) न्यायिक नजीर

141. कार्ल डॉयच ने राजनीतिक प्रणालियों को किसके संदर्भ में अवधारणाबद्ध किया?
(A) शक्ति और प्रभुत्व
(B) संरचनाएं और कार्य
(C) सूचना और संचार का प्रवाह
(D) मांगें और समर्थन

142. सूची I को सूची II के साथ सुमेलित करें।
सूची I: (अभिजन सिद्धांतकार)
P. विल्फ्रेडो पेरेटो

Q. गेटानो मोस्का
R. रॉबर्ट मिचल्स
S. सी. राइट मिल्स

सूची II: (प्रमुख विचार)
1. शक्ति अभिजन
2. अल्पतंत्र का लौह नियम
3. शासक वर्ग और राजनीतिक सूत्र
4. अभिजन का संचलन

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:
(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-4, Q-3, R-2, S-1
(C) P-4, Q-2, R-3, S-1
(D) P-1, Q-3, R-2, S-4

143. पारंपरिक दृष्टिकोण का उपयोग करने वाले अध्ययन का केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा होगा?
(A) एक विशिष्ट जनसांख्यिकीय समूह का मतदान व्यवहार।
(B) फ्रांसीसी राष्ट्रपति पद की संवैधानिक शक्तियां।
(C) भारत में राजनीतिक दृष्टिकोण पर जनसंचार माध्यमों का प्रभाव।
(D) लैटिन अमेरिका में सामाजिक आंदोलनों की भूमिका।

144. यह विचार कि एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सहभागी, प्रजाभावी और संकीर्ण तत्वों के मिश्रण वाली संस्कृति की आवश्यकता होती है, कहलाती है:
(A) नागरिक संस्कृति
(B) शक्ति अभिजन
(C) इतिहास का अंत
(D) राजनीतिक विकास

145. सरकार के अंगों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. विधायिका कानून बनाने वाला निकाय है।
2. कार्यपालिका कानूनों को लागू करती है।
3. न्यायपालिका कानूनों की व्याख्या करती है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3

146. 'अविश्वास प्रस्ताव' किस व्यवस्था से संबंधित है?
(A) संसदीय प्रणाली
(B) राष्ट्रपति प्रणाली
(C) सत्तावादी प्रणाली
(D) संघीय प्रणाली

147. अभिजनवादी सिद्धांत की एक मूल मान्यता यह है कि जनसमूह काफी हद तक है:
(A) राजनीतिक रूप से सक्रिय और संलग्न।
(B) तर्कसंगत और सुविज्ञ।
(C) उदासीन, अक्षम और असंगठित।
(D) शासन में भाग लेने के लिए उत्सुक।

148. व्यवस्था दृष्टिकोण राजनीतिक व्यवस्था को किस लिए विक्षोभों पर प्रतिक्रिया करते हुए देखता है?
(A) पूर्ण संतुलन की स्थिति प्राप्त करने के लिए।
(B) अस्तित्व बनाए रखने और खुद को संरक्षित करने के लिए।
(C) अपनी शक्ति और नियंत्रण का विस्तार करने के लिए।
(D) सरकार के एक पृथक स्वरूप में संक्रमण के लिए।

149. राजनीतिक विकास में 'पहचान का संकट' किस समस्या को संदर्भित करता है?
(A) सरकारी प्राधिकार के वैध आधार पर निर्णय लेना।
(B) राज्य की सीमाओं तक सरकारी प्राधिकार का विस्तार करना।
(C) विभिन्न जातीय या क्षेत्रीय समूहों को एक एकल राष्ट्रीय पहचान में एकीकृत करना।
(D) सरकार में अधिक सहभागिता की जन मांगों को पूरा करना।

150. निम्नलिखित दृष्टिकोणों को उनके उद्भव के कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें:
1. व्यवस्था दृष्टिकोण
2. पारंपरिक संस्थावाद
3. संरचनात्मक-प्रकार्यवाद
4. उत्तर-व्यवहारवाद

(A) 2, 1, 3, 4
(B) 2, 3, 1, 4
(C) 1, 2, 3, 4
(D) 2, 1, 4, 3

151. कौन सा कथन राज्य के मार्क्सवादी दृष्टिकोण का गलत वर्णन करता है?
(A) राज्य 'अधिसंरचना' का हिस्सा है।
(B) राज्य आर्थिक रूप से प्रभावी वर्ग का एक साधन है।
(C) राज्य एक तटस्थ निकाय है जो पूरे समाज के हितों की सेवा करता है।
(D) साम्यवादी समाज में राज्य 'विलुप्त' हो जाएगा।

152. तुलनात्मक संदर्भ में, 'न्यायिक सक्रियता' का तात्पर्य है:
(A) न्यायपालिका की विधायी शाखा के प्रति झुकने की प्रवृत्ति।
(B) कानूनों को निरस्त करने या नीति में हस्तक्षेप करने की न्यायपालिका की इच्छा।
(C) राजनीतिक संबंधों के आधार पर न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया।
(D) न्यायाधीशों के चुनाव लड़ने की कानूनी आवश्यकता।

153. 'राजनीतिक समाजीकरण', 'राजनीतिक भर्ती' से इस अर्थ में भिन्न है कि समाजीकरण का अर्थ है:

Click Here to Buy book on Amazon

(A) राजनीतिक पद के लिए लोगों का चयन करना, जबकि भर्ती मूल्यों को सीखने के बारे में है।
(B) राजनीतिक मूल्यों को सीखना, जबकि भर्ती भूमिकाओं के लिए लोगों का चयन करने के बारे में है।
(C) सूचना का प्रवाह, जबकि भर्ती अभिजन सिद्धांत के बारे में है।
(D) विधायिका के कार्य, जबकि भर्ती कार्यपालिका के बारे में है।

154. 'प्रतिस्पर्धी अभिजनवाद' के सिद्धांत में, सामान्य नागरिक की भूमिका है:
(A) नीति निर्धारण में सक्रिय रूप से भाग लेना।
(B) यह चुनना कि नेताओं का कौन सा दल शासन करेगा।
(C) सभी प्रमुख मुद्दों पर जनमत संग्रह कराना।
(D) सरकार के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन करना।

155. नीचे दो कथन दिए गए हैं:
कथन I: एकसदनीय विधायिका अक्सर छोटे, एकात्मक राज्यों में पाई जाती है।
कथन II: द्विसदनीय विधायिका अक्सर बड़े, संघीय राज्यों में पाई जाती है।
(A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं।
(C) कथन I सत्य है, लेकिन कथन II असत्य है।
(D) कथन I असत्य है, लेकिन कथन II सत्य है।

156. एक विषय के रूप में तुलनात्मक राजनीति का विकास किस दिशा में बदलाव का वर्णन करता है?
(A) विशेष से सामान्य की ओर।
(B) विश्लेषण से विवरण की ओर।
(C) सिद्धांत से व्यवहार की ओर।
(D) गैर-पश्चिमी से पश्चिमी केंद्र की ओर।

157. डेविड ईस्टन ने राजनीति को "समाज के लिए _____ के आधिकारिक आवंटन" के रूप में परिभाषित किया।
(A) संसाधनों
(B) मूल्यों
(C) शक्ति
(D) न्याय

158. संसदीय प्रणाली में 'शक्तियों के संलयन' का अर्थ है कि:
(A) न्यायपालिका का विधायिका में विलय हो गया है।
(B) राष्ट्राध्यक्ष और सरकार के प्रमुख एक ही व्यक्ति होते हैं।
(C) राष्ट्रीय और स्थानीय सरकारों का एक ही प्राधिकार में विलय हो गया है।
(D) कार्यकारी और विधायी शाखाएं परस्पर संबद्ध और एक-दूसरे पर निर्भर हैं।

159. राजनीतिक आधुनिकीकरण के शुरुआती सिद्धांतों की आलोचना किसके लिए की गई थी?
(A) यह मानना कि समाज एक पूर्व निर्धारित और निश्चित अंतिम बिंदु की ओर बढ़ते हैं।
(B) राजनीति में विशेष रूप से डिजिटल तकनीक की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करना।
(C) संस्थागत परिवर्तन पर सांस्कृतिक कारकों के प्रभाव की अनदेखी करना।
(D) अधिकांश विद्वानों के लिए अत्यधिक जटिल और सैद्धांतिक रूप से कठिन होना।

160. एक ऐसी राजनीतिक संस्कृति जिसमें नागरिक आगत प्रक्रिया में सक्रिय होते हैं, कहलाती है:
(A) एक संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति।
(B) एक सहभागी राजनीतिक संस्कृति।
(C) एक प्रजाभावी राजनीतिक संस्कृति।
(D) एक खंडित राजनीतिक संस्कृति।

161. 'राजनीतिक सूत्र' के विचार का श्रेय किस शास्त्रीय अभिजन सिद्धांतकार को दिया जाता है?
(A) विल्फ्रेडो पेरेटो
(B) रॉबर्ट मिचल्स
(C) गेटानो मोस्का
(D) सी. राइट मिल्स

162. संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य है:
(A) राज्य निर्माण का ऐतिहासिक विवरण प्रदान करना।
(B) यह समझना कि विभिन्न प्रणालियों में संरचनाएं आवश्यक कार्य कैसे निष्पादित करती हैं।
(C) पूंजीवादी प्रणालियों में अंतर्निहित असमानताओं की आलोचना करना।
(D) सरकार के सबसे नैतिक रूप को निर्धारित करना।

163. सरकार के अंगों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यूनाइटेड किंगडम में, कार्यपालिका विधायिका से ली जाती है।
2. संयुक्त राज्य अमेरिका में, कार्यपालिका विधायिका की वर्तमान सदस्य नहीं हो सकती।
3. यूनाइटेड किंगडम में संसदीय संप्रभुता संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में न्यायिक समीक्षा को सीमित करती है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3

164. विकास साहित्य में 'भागीदारी का संकट' उस स्थिति का वर्णन करता है जहाँ:
(A) सरकार अपने नागरिकों को मतदान के लिए प्रोत्साहित करने में असमर्थ है।
(B) सरकार को व्यवस्था में सम्मिलित होने के लिए सामाजिक समूहों से अत्यधिक मांगों का सामना करना

NODIA

पड़ता है।
(C) नागरिक राष्ट्र-राज्य के साथ जुड़ने से इनकार करते हैं।
(D) सत्तारूढ़ शासन की वैधता पर व्यापक रूप से सवाल उठाए जाते हैं।

165. कौन सी खबरें प्रसारित करनी हैं, यह निर्धारित करने में जनसंचार माध्यमों की भूमिका को किस रूप में जाना जाता है?
(A) हित प्रकटीकरण
(B) कार्यसूची-निर्धारण
(C) राजनीतिक भर्ती
(D) नियम अधिनिर्णयन

166. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।
अभिकथन (A): व्यवहारवादी दृष्टिकोण ने राजनीति के अध्ययन को अधिक वैज्ञानिक बनाने का प्रयास किया।
कारण (R): इसने मात्रात्मक विधियों और अवलोकन योग्य व्यवहार के उपयोग पर जोर दिया।
(A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(D) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

167. निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक व्यवस्था का 'निर्गत कार्य' नहीं है?
(A) नियम-निर्माण
(B) नियम-अनुप्रयोग
(C) नियम-अधिनिर्णयन
(D) हित-समूहन

168. 'शक्ति अभिजन' का विचार शास्त्रीय अभिजनवाद से इस अर्थ में भिन्न है कि:
(A) शक्ति अभिजन आधुनिक समाज के विशिष्ट क्षेत्रों से बना एक अधिक एकीकृत समूह है।
(B) शक्ति अभिजन सिद्धांत मानता है कि अभिजनों को लोकतांत्रिक माध्यमों से हटाया जा सकता है।
(C) शक्ति अभिजन केवल समाजवादी देशों पर लागू होने वाली अवधारणा है।
(D) शास्त्रीय अभिजनवादियों का मानना था कि अल्पसंख्यक द्वारा शासन एक नकारात्मक घटना थी।

169. सूची I को सूची II के साथ सुमेलित करें।
सूची I: (विकास का संकट)
P. पहचान
Q. वैधता
R. पैठ
S. भागीदारी
सूची II: (विवरण)
1. पूरे क्षेत्र पर सरकारी नियंत्रण स्थापित करना।
2. सामान्य राष्ट्रवाद की भावना का निर्माण करना।
3. निर्णय लेने में अधिक सहभागिता की जन मांगों का प्रबंधन करना।
4. शासन करने के सरकार के अधिकार की स्वीकृति सुरक्षित करना।
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:
(A) P-1, Q-3, R-2, S-4
(B) P-2, Q-4, R-1, S-3
(C) P-2, Q-1, R-4, S-3
(D) P-3, Q-4, R-1, S-2

170. तुलनात्मक राजनीति के अनुशासन का प्राथमिक केंद्र है:
(A) राज्यों के बीच संबंध।
(B) राज्यों की आंतरिक राजनीति।
(C) राजनीतिक विचारों का इतिहास।
(D) अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का कामकाज।

171. राजनीति के प्रणालीगत मॉडल में, 'निर्गत' संदर्भित करते हैं:
(A) जनमत और मतदान व्यवहार।
(B) अधिकारियों के बाध्यकारी निर्णय और कार्य।
(C) व्यवस्था में प्रवेश करने वाली मांगें और समर्थन।
(D) वह सांस्कृतिक संदर्भ जिसमें राजनीति होती है।

172. राष्ट्राध्यक्ष और सरकार के प्रमुख की भूमिकाओं का पृथक्करण किसकी विशेषता है?
(A) अधिकांश संसदीय प्रणालियाँ।
(B) अमेरिकी राष्ट्रपति प्रणाली।
(C) सभी संघीय प्रणालियाँ।
(D) सभी लोकतांत्रिक प्रणालियाँ।

173. "राजनीतिक पतन" की अवधारणा किसकी आलोचना करने के लिए प्रस्तुत की गई थी?
(A) आर्थिक कारकों पर इसका ध्यान।
(B) पारंपरिक संस्थानों पर इसका अत्यधिक जोर।
(C) इसकी यह आशावादी मान्यता कि सभी परिवर्तन प्रगति हैं और स्थिरता की ओर ले जाते हैं।
(D) इसका यूरोप-केंद्रित पूर्वाग्रह।

174. शुरुआती, रचनात्मक वर्षों के दौरान राजनीतिक समाजीकरण का कौन सा अभिकर्ता सबसे प्रभावशाली होता है?
(A) जनसंचार माध्यम
(B) परिवार
(C) मित्र समूह
(D) राजनीतिक दल

175. 'अल्पतंत्र का लौह नियम' कहता है कि:
(A) कठोर शासन सरकार का सबसे प्रभावी स्वरूप है।
(B) सभी संगठनों पर अनिवार्य रूप से एक छोटे अभिजन का प्रभुत्व हो जाता है।
(C) किसी देश का धन उसके लोहे के उत्पादन से निर्धारित होता है।
(D) जो अभिजन बलपूर्वक शासन करते हैं, वे अंततः अपदस्थ

NODIA

कर दिए जाएंगे।

176. निम्नलिखित में से कौन सी संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण की एक प्रमुख विशेषता है?
(A) यह मानता है कि सभी प्रणालियों को जीवित रहने के लिए बुनियादी कार्य करने चाहिए।
(B) यह मुख्य रूप से वर्णनात्मक और गैर-तुलनात्मक है।
(C) यह विशेष रूप से वर्ग संघर्ष की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करता है।
(D) यह आनुभविक डेटा के उपयोग को अस्वीकार करता है।

177. तुलनात्मक राजनीति के पारंपरिक दृष्टिकोण की "संकीर्ण" होने के लिए आलोचना की गई थी क्योंकि इसने:
(A) राष्ट्रीय सरकार के बजाय स्थानीय सरकार पर ध्यान केंद्रित किया।
(B) सीमित दायरा रखा, जो मुख्य रूप से पश्चिमी संस्थानों का अध्ययन करता था।
(C) राजनीतिक भागीदारी को लेकर अत्यधिक चिंता प्रकट की।
(D) बहुत सैद्धांतिक और अमूर्त स्वरूप रखा।

178. विधायिकाओं के संदर्भ में "द्विसदनीयता" का क्या अर्थ है?
(A) विधायकों का दो वर्ष के लिए पद धारण करने की प्रथा।
(B) दो पृथक कक्षों या सदनों से बनी एक विधायिका।
(C) एक ऐसी प्रणाली जहाँ विधायी और कार्यकारी शक्तियाँ जुड़ी हुई हों।
(D) एक विधायिका जिसकी वर्ष में दो बार बैठक होती है।

179. नागरिक संस्कृति ढांचे में, एक 'प्रजाभावी' राजनीतिक संस्कृति वह है जहाँ नागरिक:
(A) राजनीतिक व्यवस्था का कोई ज्ञान नहीं रखते।
(B) राजनीतिक परिणामों को आकार देने में सक्रिय रूप से संलग्न हैं।
(C) उसे प्रभावित करने का प्रयास किए बिना चुपचाप सरकार की आज्ञा का पालन करते हैं।
(D) उच्च भागीदारी और उच्च आज्ञाकारिता का मिश्रण रखते हैं।

180. जोसेफ शुम्पेटर के लोकतंत्र के सिद्धांत को अक्सर इस रूप में वर्णित किया जाता है:
(A) सहभागी
(B) विमर्शी
(C) अभिजनवादी या प्रक्रियात्मक
(D) मार्क्सवादी

181. निम्नलिखित में से कौन व्यवस्था सिद्धांत में 'रूपांतरण प्रक्रिया' का सबसे अच्छा वर्णन करता है?
(A) प्रचलित राजनीतिक संस्कृति में नागरिकों का समाजीकरण।
(B) जनता की मांगों और समर्थनों का नीतियों में परिवर्तन।
(C) नीतियों से मिलने वाली प्रतिक्रिया जो भविष्य की सामाजिक मांगों को प्रभावित करती है।
(D) एक प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के माध्यम से राजनीतिक नेताओं का चुनाव।

182. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।
अभिकथन (A): राष्ट्रपति प्रणाली में शक्ति को सीमित करने के लिए लिखित संविधान और न्यायिक समीक्षा आवश्यक है।
कारण (R): विधायिका के प्रति कार्यकारी जवाबदेही की अनुपस्थिति में, कानूनी नियंत्रण शक्ति के दुरुपयोग को रोकते हैं।
(A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(D) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

183. सत्तारूढ़ समूहों की उत्पत्ति और संचलन का अध्ययन किसका केंद्र है?
(A) व्यवस्था सिद्धांत
(B) अभिजन सिद्धांत
(C) संरचनात्मक प्रकार्यवाद
(D) राजनीतिक विकास सिद्धांत

184. व्यवहारवाद की 'उत्तर-व्यवहारवादी' आलोचना ने तर्क दिया कि:
(A) अनुसंधान सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए प्रासंगिक होना चाहिए।
(B) राजनीति विज्ञान एक विशुद्ध रूप से ऐतिहासिक अनुशासन होना चाहिए।
(C) केवल औपचारिक संस्थान ही अध्ययन के योग्य हैं।
(D) मात्रात्मक विधियों को त्याग दिया जाना चाहिए।

185. राजनीतिक संचार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह सरकार से सूचना का एकतरफा प्रवाह है।
2. जनसंचार माध्यम आधुनिक संचार में प्रमुख संस्थान हैं।
3. यह समाजीकरण और हित प्रकटीकरण में भूमिका निभाता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3

186. तुलनात्मक विश्लेषण में, यूनाइटेड किंगडम की सरकार को इस रूप में वर्गीकृत किया गया है:
(A) एक संसदीय संवैधानिक राजतंत्र
(B) एक राष्ट्रपति गणराज्य
(C) एक अर्ध-राष्ट्रपति प्रणाली
(D) एक संघीय गणराज्य

Downloaded from www.pdf.tube

187. मार्क्सवादी अवधारणा 'अधिसंरचना' में निम्नलिखित में से किसे छोड़कर सभी शामिल हैं?
(A) कानूनी प्रणाली
(B) उत्पादन की विधि
(C) राजनीतिक संस्थान
(D) प्रभावी विचारधारा

188. 'राजनीतिक पतन' शब्द वर्णन करता है:
(A) किसी राजनीतिक शासन की स्वाभाविक जरावस्था की प्रक्रिया।
(B) व्यक्तिगत राजनेताओं का भ्रष्टाचार।
(C) किसी राज्य की सैन्य शक्ति में गिरावट।
(D) तीव्र परिवर्तन के सम्मुख राजनीतिक संस्थाओं का चरमराना।

189. संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक ढांचे में, 'हित समूहन' सामान्यतः किसके द्वारा किया जाता है?
(A) हित समूह और सामाजिक आंदोलन
(B) राजनीतिक दल
(C) नौकरशाही
(D) न्यायपालिका

190. अभिजनवादी सिद्धांत बताता है कि चुनावों का प्राथमिक उद्देश्य है:
(A) प्रत्यक्ष जन संप्रभुता सुनिश्चित करना।
(B) सत्तारूढ़ अभिजन को चुनने के लिए एक शांतिपूर्ण साधन प्रदान करना।
(C) मतदाताओं की नीतिगत प्राथमिकताओं को सटीक रूप से प्रतिबिंबित करना।
(D) जनता को राजनीतिक मुद्दों के बारे में शिक्षित करना।

191. विधायी और न्यायिक अंगों के बीच एक मुख्य अंतर यह है कि:
(A) विधायिका सामान्य नियम बनाती है, जबकि न्यायपालिका उन्हें विशिष्ट मामलों पर लागू करती है।
(B) न्यायपालिका सामान्य नियम बनाती है, जबकि विधायिका उन्हें लागू करती है।
(C) विधायिका नियुक्त की जाती है, जबकि न्यायपालिका निर्वाचित होती है।
(D) न्यायपालिका सभी प्रणालियों में विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है।

192. कौन सा दृष्टिकोण 'आगत', 'निर्गत', 'फीडबैक' और 'पर्यावरण' से सबसे अधिक संबंधित है?
(A) मार्क्सवादी दृष्टिकोण
(B) व्यवस्था दृष्टिकोण
(C) पारंपरिक दृष्टिकोण
(D) अभिजन सिद्धांत

193. राजनीतिक संस्कृति का तुलनात्मक अध्ययन किस पर केंद्रित है?
(A) विभिन्न देशों के संवैधानिक कानून।
(B) राजनीतिक वस्तुओं के प्रति मनोवैज्ञानिक अभिवृत्ति के स्वरूप।
(C) विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों का आर्थिक निष्पादन।
(D) सरकारी संस्थानों की औपचारिक संरचना।

NODIA

194. नीचे दो कथन दिए गए हैं:
कथन I: तुलनात्मक राजनीति पद्धतिगत कठोरता की ओर रुझान दर्शाती है।
कथन II: यह अनुशासन कई देशों में पैटर्न को समझाने की ओर बढ़ा है।
(A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं।
(C) कथन I सत्य है, लेकिन कथन II असत्य है।
(D) कथन I असत्य है, लेकिन कथन II सत्य है।

195. अभिजन सिद्धांत में, 'शेर' वे अभिजन हैं जो _____ के माध्यम से शासन करते हैं, जबकि 'लोमड़ी' _____ के माध्यम से शासन करती हैं।
(A) सहमति; बल प्रयोग
(B) बल; अनुनय और चतुराई
(C) परंपरा; करिश्मा
(D) धन; सैन्य शक्ति

196. सूची I को सूची II के साथ सुमेलित करें।
सूची I: (सरकार प्रणाली)
P. राष्ट्रपति
Q. संसदीय
R. अर्ध-राष्ट्रपति
S. एकात्मक
सूची II: (प्रमुख विशेषता)
1. कार्यकारी और विधायी शक्ति का संलयन।
2. दोहरी कार्यपालिका।
3. शक्तियों का सख्त पृथक्करण।
4. शक्ति का केंद्रीकरण, उप-इकाइयों के साथ साझा नहीं किया जाता।
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:
(A) P-3, Q-1, R-2, S-4
(B) P-1, Q-3, R-2, S-4
(C) P-3, Q-2, R-1, S-4
(D) P-1, Q-2, R-3, S-4

197. राजनीतिक आधुनिकीकरण में वैधता का बदलाव कहाँ से कहाँ होता है?
(A) करिश्माई से पारंपरिक सत्ता की ओर।
(B) तर्कसंगत-कानूनी से करिश्माई सत्ता की ओर।
(C) पारंपरिक से तर्कसंगत-कानूनी सत्ता की ओर।
(D) तर्कसंगत-कानूनी से पारंपरिक सत्ता की ओर।

198. परिवार, विद्यालय और जनसंचार माध्यम नागरिकों के राजनीतिक विचारों को कैसे आकार देते हैं, इसका अध्ययन है:
(A) राजनीतिक संचार
(B) राजनीतिक समाजीकरण
(C) राजनीतिक विकास
(D) राजनीतिक अर्थव्यवस्था

199. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।
अभिकथन (A): एक विषय के रूप में तुलनात्मक राजनीति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से भिन्न है।
कारण (R): तुलनात्मक राजनीति देशों के 'भीतर' की व्यवस्थाओं पर ध्यान केंद्रित करती है।
(A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(D) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

200. "अल्पतंत्र का लौह नियम" की अवधारणा तर्क देती है कि:
(A) किसी भी बड़े संगठन में नेतृत्व एक स्वयं को बनाए रखने वाला अल्पतंत्र बन जाता है।
(B) बड़े संगठनों में लोकतंत्र सबसे प्रभावी होता है।
(C) समाजवादी दल अभिजन प्रभुत्व से अछूते हैं।
(D) अल्पतंत्र केवल पूंजीवादी समाजों की एक विशेषता है।

201. राजनीतिक व्यवस्था के 'निर्गत' को सबसे अच्छी तरह इस रूप में समझा जाता है:
(A) व्यवस्था पर की गई मांगें।
(B) व्यवस्था को दिया गया समर्थन।
(C) व्यवस्था के आधिकारिक निर्णय और नीतियां।
(D) समाज के सांस्कृतिक मानदंड।

202. निम्नलिखित में से कौन सी पारंपरिक दृष्टिकोण की विशेषता नहीं है?
(A) आदर्शात्मक पूर्वाग्रह
(B) औपचारिक संस्थाओं पर ध्यान
(C) वर्णनात्मक प्रकृति
(D) आनुभविक डेटा और सांख्यिकीय विश्लेषण पर जोर

203. सरकार के कार्यकारी अंग की प्राथमिक भूमिका है:
(A) कानून बनाना
(B) अधिनिर्णयन
(C) कार्यान्वयन
(D) प्रतिनिधित्व

204. 'राजनीतिक विकास' शब्द सबसे सटीक रूप से किसके साथ जुड़ा हुआ है?
(A) अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों का अध्ययन।
(B) राजनीतिक व्यवस्था की क्षमता और संरचना में परिवर्तन की प्रक्रिया।
(C) सरकार के सर्वोत्तम स्वरूप पर दार्शनिक बहस।
(D) एकल चुनाव अभियान का विश्लेषण।

205. राजनीतिक संस्कृति के अध्ययन में निम्नलिखित में से कौन सा एक कालजयी कार्य है?
(A) द सिविक कल्चर
(B) द पॉलिटिकल सिस्टम
(C) द पावर एलीट
(D) पॉलिटिकल पार्टीज

206. लोकतंत्र के अभिजनवादी सिद्धांत के अनुसार, समाज में वास्तविक शक्ति किसके पास होती है?
(A) सामान्य मतदाता
(B) एक छोटा, एकजुट सत्तारूढ़ अल्पसंख्यक
(C) निर्वाचित प्रतिनिधि
(D) विभिन्न प्रकार के प्रतिस्पर्धी हित समूह

207. एक ऐसी व्यवस्था जहाँ कार्यपालिका विधायिका से ली जाती है और उसके विश्वास पर निर्भर करती है, वह है:
(A) एक राष्ट्रपति प्रणाली
(B) एक संसदीय प्रणाली
(C) एक न्यायिक प्रणाली
(D) एक संघीय प्रणाली

208. संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण किसके लिए विकसित किया गया था?
(A) राजनीति में विशेष रूप से वर्ग की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करने के लिए।
(B) ऐतिहासिक विवरण के महत्व पर पुनः जोर देने के लिए।
(C) एक विशिष्ट राजनीतिक विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए।
(D) पश्चिमी और गैर-पश्चिमी राजनीतिक प्रणालियों की तुलना की सुविधा के लिए।

209. निम्नलिखित में से कौन तुलनात्मक राजनीति की प्राथमिक चिंता नहीं होगी?
(A) अमेरिकी राष्ट्रपति और ब्रिटिश प्रधानमंत्री की शक्तियों की तुलना।
(B) दो देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते की बातचीत।
(C) लैटिन अमेरिका में सैन्य तख्तापलट के कारणों का विश्लेषण।
(D) विभिन्न लोकतांत्रिक देशों में मतदान को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन।

210. राजनीतिक अभिजनों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. शास्त्रीय अभिजन सिद्धांत मानता है कि अल्पसंख्यक द्वारा शासन अपरिहार्य है।
2. सी. राइट मिल्स ने 20वीं सदी के मध्य के अमेरिका में

Click Here to Buy book on Amazon

एक एकीकृत "शक्ति अभिजन" की पहचान की।
3. शुम्पेटर ने लोकतंत्र को अभिजनों के बीच एक प्रतिस्पर्धा के रूप में देखा।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3

211. व्यवस्था विश्लेषण में, 'फीडबैक' उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके द्वारा:
(A) सरकार अपने निर्णयों को जनता तक पहुँचाती है।
(B) सरकारी कार्रवाई के बारे में जानकारी वापस व्यवस्था में भेजी जाती है।
(C) जनता सरकार के समक्ष अपनी मांगें व्यक्त करती है।
(D) अत्यधिक तनाव के कारण व्यवस्था चरमरा जाती है।

212. नीचे दो कथन दिए गए हैं:
कथन I: संसदीय संप्रभुता वाली व्यवस्था में न्यायपालिका सामान्यतः कमजोर होती है।
कथन II: यूनाइटेड किंगडम में, अदालतें कानून को निरस्त नहीं कर सकतीं, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में, उच्चतम न्यायालय कर सकता है।
(A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं।
(C) कथन I सत्य है, लेकिन कथन II असत्य है।
(D) कथन I असत्य है, लेकिन कथन II सत्य है।

213. राजनीतिक विकास में एक केंद्रीय तर्क यह है कि:
(A) आर्थिक विकास सभी राष्ट्रों के लिए प्राथमिक और सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है।
(B) प्राथमिक चुनौती प्रभावी संस्थानों के निर्माण से जुड़ी है।
(C) आर्थिक सफलता प्राप्त करने के लिए लोकतंत्र एक आवश्यक पूर्व शर्त है।
(D) पारंपरिक मूल्य आधुनिक प्रगति के मार्ग में मौलिक बाधा हैं।

214. जनता किन मुद्दों को महत्वपूर्ण मानती है, इसे प्रभावित करने की संचार माध्यमों की क्षमता किसका उदाहरण है?
(A) राजनीतिक संचार
(B) राजनीतिक समाजीकरण
(C) हित प्रकटीकरण
(D) नियम अनुप्रयोग

215. 'अभिजनों का संचलन' वर्णन करता है:
(A) वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जनसमूह अभिजन को उखाड़ फेंकता है।
(B) एक सत्तारूढ़ अभिजन का दूसरे द्वारा प्रतिस्थापन।
(C) राजनीतिक नेताओं की दैनिक दिनचर्या।
(D) अभिजनों के बीच संचार नेटवर्क।

216. विधायिका के 'निगरानी' कार्य का तात्पर्य है:
(A) नए कानूनों को पारित करना।
(B) कार्यकारी शाखा की निगरानी और पर्यवेक्षण।
(C) निर्वाचन क्षेत्र के हितों का प्रतिनिधित्व।
(D) संविधान का संशोधन।

217. तुलनात्मक राजनीति के प्रति मार्क्सवादी दृष्टिकोण किस पर ध्यान केंद्रित करता है?
(A) मतदाताओं की मनोवैज्ञानिक अभिवृत्तियाँ।
(B) जिस प्रकार वर्ग संरचनाएं राजनीतिक प्रणालियों को आकार देती हैं।
(C) स्थिरता बनाए रखने के लिए सभी राजनीतिक प्रणालियों द्वारा किए जाने वाले कार्य।
(D) राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों की औपचारिक शक्तियां।

218. नागरिक संस्कृति मॉडल में, 'नागरिक संस्कृति' किसका मिश्रण है?
(A) संकीर्ण, प्रजाभावी और अभिजनवादी
(B) संकीर्ण, प्रजाभावी और सहभागी
(C) लोकतांत्रिक, सत्तावादी और सर्वाधिकारवादी
(D) पारंपरिक, आधुनिक और उत्तर-आधुनिक

219. राष्ट्रपति प्रणाली की परिभाषित विशेषता है:
(A) सरकार का प्रमुख राष्ट्राध्यक्ष भी होता है।
(B) कार्यकारी और विधायी शाखाएं पृथक रूप से निर्वाचित और स्वतंत्र होती हैं।
(C) मंत्रिमंडल विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है।
(D) राष्ट्राध्यक्ष एक सम्राट होता है।

220. 'राजनीतिक समाजीकरण' की अवधारणा किसे संदर्भित करती है?
(A) राजनीतिक दलों के गठन की प्रक्रिया।
(B) राजनीतिक अभिविन्यास प्राप्त करने की आजीवन प्रक्रिया।
(C) समाजवाद को बढ़ावा देने का सरकार का प्रयास।
(D) राजनीतिक नेताओं के बीच औपचारिक बातचीत।

221. निम्नलिखित विचारकों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें:
1. सी. राइट मिल्स
2. गेटानो मोस्का
3. रॉबर्ट मिचल्स
4. विल्फ्रेडो पेरेटो

(A) 2, 4, 3, 1
(B) 4, 2, 1, 3
(C) 1, 3, 4, 2
(D) 2, 3, 1, 4

222. संरचनात्मक-प्रकार्यवाद की 'हित प्रकटीकरण' की अवधारणा संदर्भित करती है:
(A) सरकारी नीति का निर्माण।

NODIA

267. संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम में कार्यपालिका के बीच मुख्य अंतर यह है कि:
(A) संयुक्त राज्य अमेरिका में कार्यपालिका है, जबकि यूनाइटेड किंगडम में नहीं।
(B) संयुक्त राज्य अमेरिका में एकल कार्यपालिका है, जबकि यूनाइटेड किंगडम में दोहरी कार्यपालिका है।
(C) अमेरिकी कार्यपालिका विधायिका से पृथक है, जबकि यूनाइटेड किंगडम की कार्यपालिका उसी से निर्मित होती है।
(D) अमेरिकी कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित होता है, जबकि यूनाइटेड किंगडम की कार्यपालिका का कार्यकाल विधायी विश्वास पर निर्भर करता है।

268. राजनीतिक विकास पर लुसियन पाई का कार्य किसके प्रति अपने केंद्र के लिए जाना जाता है?
(A) "इतिहास का अंत" सिद्धांत।
(B) विकास के संकट, जैसे पहचान, वैधता और भागीदारी।
(C) राज्य के व्यवहार को आकार देने में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की भूमिका।
(D) विकास की विशुद्ध रूप से आर्थिक परिभाषा।

269. सूचना का वह प्रवाह जिसका राजनीतिक प्रक्रिया पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, कहलाता है:
(A) राजनीतिक समाजीकरण
(B) राजनीतिक भर्ती
(C) राजनीतिक संचार
(D) राजनीतिक संस्कृति

270. सूची I को सूची II के साथ सुमेलित करें।
सूची I: (राजनीतिक संस्कृति का प्रकार)
P. संकीर्ण
Q. प्रजाभावी
R. सहभागी
S. नागरिक संस्कृति
सूची II: (नागरिक का अभिविन्यास)
1. व्यवस्था के प्रति उन्मुख और आगत प्रक्रियाओं में सक्रिय।
2. संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था के प्रति अनभिज्ञ।
3. निर्गत के प्रति जागरूक लेकिन व्यवस्था के प्रति निष्क्रिय और आज्ञाकारी।
4. संकीर्ण, प्रजाभावी और सहभागी अभिविन्यासों का मिश्रण।
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:
(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-2, Q-3, R-1, S-4
(C) P-3, Q-1, R-2, S-4
(D) P-2, Q-1, R-3, S-4

271. सी. राइट मिल्स की 'द पावर एलीट' किस सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य का उदाहरण है?
(A) बहुलवाद
(B) अभिजनवाद
(C) मार्क्सवाद
(D) प्रकार्यवाद

272. तुलनात्मक राजनीति में 'व्यवहारवादी' आंदोलन ने किस पर जोर दिया?
(A) संस्थाओं के ऐतिहासिक संदर्भ का अध्ययन करना।
(B) श्रेष्ठ राज्य के आदर्शात्मक सिद्धांतों का विकास करना।
(C) राजनीतिक स्थितियों में व्यक्ति कैसा व्यवहार करते हैं, इसका अध्ययन करने के लिए आनुभविक विधियों का उपयोग करना।
(D) केवल सरकारी अंगों की कानूनी शक्तियों पर ध्यान केंद्रित करना।

273. कार्यकारी शाखा द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निष्पादित किया जाता है?
(A) नियम-निर्माण
(B) नियम-अनुप्रयोग
(C) नियम-अधिनिर्णयन
(D) हित-प्रकटीकरण

274. 'राजनीतिक आधुनिकीकरण' की अवधारणा में निम्नलिखित में से किसे छोड़कर सभी शामिल हैं?
(A) राजनीतिक संस्कृति का धर्मनिरपेक्षीकरण।
(B) राजनीतिक संरचनाओं का विभेदीकरण और विशिष्टीकरण।
(C) राजनीति में नागरिकों की भागीदारी में वृद्धि।
(D) प्राधिकार के पारंपरिक स्रोतों का सुदृढ़ीकरण।

275. आलमंड और वर्बा के ढांचे में, 'सहभागी' राजनीतिक संस्कृति क्या है?
(A) एक ऐसी संस्कृति जहाँ लोग राजनीति से अनभिज्ञ होते हैं।
(B) एक ऐसी संस्कृति जहाँ लोग सरकार की निष्क्रिय प्रजा होते हैं।
(C) एक ऐसी संस्कृति जहाँ नागरिक राजनीतिक प्रक्रिया के प्रति जागरूक और उसमें सम्मिलित होते हैं।
(D) एक ऐसी संस्कृति जो पारंपरिक से आधुनिक की ओर परिवर्तित हो रही है।

276. लोकतंत्र का अभिजनवादी सिद्धांत, विशेष रूप से जोसेफ शुम्पेटर द्वारा प्रतिपादित, लोकतंत्र को किस रूप में पुनर्परिभाषित करता है?
(A) जनता का प्रत्यक्ष शासन।
(B) सरकार की एक ऐसी प्रणाली जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को अधिकतम करती है।
(C) सरकार को चुनने और अधिकृत करने की एक विधि।
(D) सामान्य इच्छा की प्राप्ति।

277. राजनीतिक विश्लेषण का 'व्यवस्था दृष्टिकोण' किसके साथ जुड़ा हुआ है?

Downloaded from www.pdf.tube

STUDYING FROM PDFs?

THINK AGAIN.

If you are studying only from PDFs,
you are wasting valuable time.

Research shows that learning from

PRINTED BOOKS has up to

4× HIGHER RETENTION

than studying from screens.

PRINT BOOK = BETTER MEMORY

PDF = LOWER RETENTION

Those who study from **PRINTED BOOKS**
move **AHEAD.**

Others are left **BEHIND**
in competition.

In competitive exams,
being average is not enough.

STAY ONE STEP AHEAD.

(A) राजनीतिक समाजीकरण
(B) राजनीतिक आधुनिकीकरण
(C) राजनीतिक संचार
(D) राजनीतिक संस्कृति

234. प्रणालीगत मॉडल में, 'राजनीतिक व्यवस्था' उन अंतःक्रियाओं का समूह है जिनके माध्यम से:
(A) अर्थव्यवस्था वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करती है।
(B) समाज के लिए मूल्यों का आधिकारिक रूप से आवंटन किया जाता है।
(C) सांस्कृतिक मानदंड पीढ़ियों तक प्रेषित होते हैं।
(D) एक राष्ट्र बाह्य खतरों से स्वयं की रक्षा करता है।

235. नीचे दो कथन दिए गए हैं:
कथन I: विधायिका मुख्य रूप से कानून बनाने के लिए उत्तरदायी है।
कथन II: न्यायपालिका मुख्य रूप से कानूनों की व्याख्या करने के लिए उत्तरदायी है।
(A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं।
(C) कथन I सत्य है, लेकिन कथन II असत्य है।
(D) कथन I असत्य है, लेकिन कथन II सत्य है।

236. एक ऐसी संस्कृति जहाँ नागरिकों में उच्च जागरूकता और राजनीतिक प्रभावकारिता होती है, कहलाती है:
(A) एक प्रजाभावी संस्कृति
(B) एक संकीर्ण संस्कृति
(C) एक सहभागी संस्कृति
(D) एक विमुख संस्कृति

237. राज्य का मार्क्सवादी सिद्धांत प्रतिपादित करता है कि राज्य किसका साधन है?
(A) राष्ट्रीय एकता
(B) सामाजिक न्याय
(C) प्रभावी आर्थिक वर्ग
(D) सामान्य इच्छा

238. सी. राइट मिल्स की "द पावर एलीट" के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. इसने संयुक्त राज्य अमेरिका को नियंत्रित करने वाले एक एकल अभिजन समूह की पहचान की।
2. यह अभिजन कॉर्पोरेट, सैन्य और राजनीतिक क्षेत्रों से बना था।
3. यह अभिजन मौलिक रूप से जनता के प्रति जवाबदेह नहीं था।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3

239. राजनीति विज्ञान में 'तुलनात्मक पद्धति' क्या प्रयास करती है?
(A) एक राजनीतिक व्यवस्था की दूसरों पर श्रेष्ठता सिद्ध करना।
(B) किसी एक देश की राजनीतिक संस्थाओं के इतिहास का वर्णन करना।
(C) विभिन्न देशों में समानताओं और अंतरों की पहचान करना और उनकी व्याख्या करना।
(D) राजनीति के ऐसे सार्वभौमिक नियम बनाना जो सभी संदर्भों में सत्य हों।

240. 'राजनीतिक समाजीकरण' की अवधारणा किससे संबंधित है?
(A) व्यक्तियों को राजनीतिक भूमिकाओं में कैसे भर्ती किया जाता है।
(B) समाज में राजनीतिक जानकारी कैसे प्रेषित होती है।
(C) व्यक्ति अपने राजनीतिक मूल्यों, विश्वासों और अभिवृत्तियों को कैसे प्राप्त करते हैं।
(D) राजनीतिक प्रणालियाँ अपनी क्षमता और प्रभावशीलता कैसे बढ़ाती हैं।

241. सरकार का कौन सा अंग 'नियम अधिनिर्णयन' के लिए उत्तरदायी है?
(A) कार्यपालिका
(B) विधायिका
(C) न्यायपालिका
(D) निर्वाचक मंडल

NODIA

242. तुलनात्मक राजनीति के पारंपरिक दृष्टिकोण की निम्नलिखित सभी के लिए आलोचना की गई थी, सिवाय:
(A) अत्यधिक औपचारिक और कानूनी होने के लिए।
(B) व्याख्यात्मक के बजाय बड़े पैमाने पर वर्णनात्मक होने के लिए।
(C) अपने केंद्र में यूरोप-केंद्रित होने के लिए।
(D) मात्रात्मक डेटा पर अत्यधिक निर्भर होने के लिए।

243. राजनीतिक विकास के संदर्भ में, "पैठ का संकट" किसे संदर्भित करता है?
(A) सरकार के लिए जन वैधता प्राप्त करना।
(B) विभिन्न उप-राष्ट्रीय समूहों को एकीकृत करना।
(C) सरकार की प्रशासनिक पहुंच को दूरस्थ क्षेत्रों तक विस्तारित करना।
(D) विदेशी सांस्कृतिक प्रभावों के प्रवेश का प्रबंधन करना।

244. प्रतिस्पर्धी अभिजनवाद के सिद्धांत को विशेष रूप से किसके द्वारा व्यक्त किया गया था?
(A) रॉबर्ट मिचल्स
(B) जोसेफ शुम्पेटर
(C) गेटानो मोस्का
(D) कार्ल मार्क्स

245. नीचे दो कथन दिए गए, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।

(B) राजनीतिक व्यवस्था के समक्ष आवश्यकताओं और मांगों को व्यक्त करने की प्रक्रिया।
(C) कानूनी विवादों का अधिनिर्णयन।
(D) नौकरशाही द्वारा कानूनों का कार्यान्वयन।

223. निम्नलिखित में से कौन आधुनिक तुलनात्मक राजनीति के 'दायरे' का सबसे अच्छा वर्णन है?
(A) यह विश्व की प्रमुख शक्तियों के संविधानों के अध्ययन तक सीमित है।
(B) इसमें वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग करते हुए राज्यों के भीतर सभी राजनीतिक गतिविधियों का अध्ययन शामिल है।
(C) यह राजनीतिक शक्ति के दार्शनिक औचित्य पर केंद्रित है।
(D) यह विशेष रुप से देशों के बीच राजनयिक संबंधों से संबंधित है।

224. संसदीय और राष्ट्रपति प्रणाली में विधायिका के बीच एक मुख्य अंतर यह है कि संसदीय प्रणाली में विधायिका:
(A) के पास न्यायिक समीक्षा की शक्ति होती है।
(B) वह निकाय है जिससे कार्यपालिका निर्मित होती है और जिसके प्रति वह जवाबदेह होती है।
(C) कार्यकारी शाखा से पूर्णतः स्वतंत्र होती है।
(D) संवैधानिक रुप से निश्चित कार्यकाल के लिए कार्य करती है जिसे कम नहीं किया जा सकता।

225. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रुप में अंकित किया गया है।
अभिकथन (A): द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तुलनात्मक राजनीति के दायरे में महत्वपूर्ण विस्तार देखा गया।
कारण (R): विकासशील देशों में कई स्वतंत्र राज्यों के उदय ने नए उदाहरण प्रदान किए।
(A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(D) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

226. वह सिद्धांत कि सभी संगठन अनिवार्य रुप से कुछ लोगों के शासन के सम्मुख झुक जाते हैं, कहलाता है:
(A) अभिजन संचलन का सिद्धांत
(B) शक्ति अभिजन सिद्धांत
(C) अल्पतंत्र का लौह नियम
(D) शासक वर्ग का सिद्धांत

227. लुसियन पाई द्वारा पहचाने गए राजनीतिक विकास के संकटों में से निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है?
(A) पहचान
(B) वैधता
(C) भागीदारी
(D) आधुनिकीकरण

228. संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक ढांचे में, 'हित समूहन' का अर्थ है कि दल:
(A) एक संकीर्ण समूह की विशिष्ट मांगों को व्यक्त करते हैं।
(B) अनेक मांगों को कुछ नीतिगत विकल्पों में समन्वित करते हैं।
(C) सरकारी निर्णयों को जनता तक पहुँचाते हैं।
(D) राजनीतिक व्यवस्था में नए सदस्यों की भर्ती करते हैं।

229. सूची I को सूची II के साथ सुमेलित करें।
सूची I: (अवधारणा)
P. राजनीतिक पतन
Q. नागरिक संस्कृति
R. राजनीतिक व्यवस्था
S. अल्पतंत्र का लौह नियम
सूची II: (विचारक)
1. डेविड ईस्टन
2. सैमुअल पी. हंटिंगटन
3. रॉबर्ट मिचल्स
4. गैब्रियल आलमंड और सिडनी वर्बा
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:
(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-2, Q-4, R-1, S-3
(C) P-3, Q-1, R-4, S-2
(D) P-2, Q-3, R-1, S-4

230. 'व्यवहारवादी दृष्टिकोण' ने किस पर जोर दिया?
(A) ऐतिहासिक विश्लेषण की प्रधानता।
(B) अनुसंधान में तथ्यों और मूल्यों के बीच सख्त पृथक्करण।
(C) मूल रुप में औपचारिक-कानूनी संस्थाओं का अध्ययन।
(D) लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए एक आदर्शात्मक प्रतिबद्धता।

231. तुलनात्मक संदर्भ में, 'शक्तियों का संलयन' की अवधारणा का सबसे अच्छा उदाहरण किसके द्वारा दिया गया है?
(A) संयुक्त राज्य अमेरिका
(B) यूनाइटेड किंगडम
(C) स्विट्जरलैंड
(D) फ्रांस

232. निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय अभिजन सिद्धांत के एक मूल विचार को सटीक रुप से दर्शाता है?
(A) समाज शासकों और शासितों में विभाजित है, और यह एक अपरिहार्य सामाजिक तथ्य है।
(B) अवसर मिलने पर जनसमूह प्रभावी स्व-शासन करने में सक्षम है।
(C) अभिजन केवल सत्तावादी राज्यों में शासन करते हैं, लोकतंत्रों में नहीं।
(D) आर्थिक धन अभिजन स्थिति का एकमात्र आधार है।

233. राजनीतिक जीवन का युक्तिकरण, विभेदीकरण और धर्मनिरपेक्षीकरण किसके घटक हैं?

Click Here to Buy book on Amazon

समाजवाद लोकतांत्रिक है।
(D) सुदृढ़ संवैधानिक सुरक्षा उपायों के माध्यम से अल्पतंत्र को रोका जा सकता है।

256. एकसदनीय विधायिका वह विधायिका है:
(A) जिसमें दो सदन होते हैं।
(B) जिसमें केवल एक सदन होता है।
(C) जो एकात्मक प्रणाली का हिस्सा होती है।
(D) जो कार्यपालिका के अधीन होती है।

257. संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक विश्लेषण में राजनीतिक दल का प्राथमिक कार्य है:
(A) हित प्रकटीकरण
(B) हित समूहन
(C) राजनीतिक समाजीकरण
(D) नियम अधिनिर्णयन

258. "समाज के लिए मूल्यों का आधिकारिक आवंटन" राजनीति की एक परिभाषा है जो किसके द्वारा दी गई है?
(A) हेरोल्ड लासवेल
(B) डेविड ईस्टन
(C) गैब्रियल आलमंड
(D) कार्ल मार्क्स

259. कार्यपालिका और विधायिका के बीच संबंधों का तुलनात्मक विश्लेषण जांच करता है:
(A) चुनावों में राजनीतिक दलों की भूमिका।
(B) शक्ति पृथक्करण बनाम शक्तियों के संलयन की प्रणालियाँ।
(C) लोकतंत्र पर आर्थिक विकास का प्रभाव।
(D) राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया।

260. सैमुअल हंटिंगटन के विकास के सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए:
1. संस्थाकरण के बिना तीव्र सामाजिक गतिशीलता पतन की ओर ले जाती है।
2. उन्होंने तीव्र लोकतंत्रीकरण के बजाय राजनीतिक व्यवस्था और स्थिरता को प्राथमिकता दी।
3. उनके कार्य ने आधुनिकीकरण सिद्धांत की आशावादी मान्यताओं की आलोचना की।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3

261. 'राजनीतिक संस्कृति' की अवधारणा किसे संदर्भित करती है?
(A) राज्य की आधिकारिक विचारधारा।
(B) राजनीतिक आचरण को नियंत्रित करने वाले कानूनों का समूह।
(C) किसी जनसंख्या के भीतर राजनीति के प्रति सामूहिक अभिवृत्तियाँ, विश्वास और भावनाएं।
(D) समाज में कलात्मक और साहित्यिक उपलब्धि का स्तर।

262. नीचे दो कथन दिए गए हैं:
कथन I: शास्त्रीय अभिजन सिद्धांतकारों का मानना था कि अल्पसंख्यक द्वारा शासन अपरिहार्य है।
कथन II: उन्होंने तर्क दिया कि यह अल्पसंख्यक के श्रेष्ठ संगठन के कारण था।
(A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं।
(C) कथन I सत्य है, लेकिन कथन II असत्य है।
(D) कथन I असत्य है, लेकिन कथन II सत्य है।

263. तुलनात्मक राजनीति में, 'न्यायिक समीक्षा' अदालतों की वह शक्ति है जिसके द्वारा वे:
(A) सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति करते हैं।
(B) चुनावों का पर्यवेक्षण करते हैं।
(C) कानूनों और सरकारी कार्यों की संवैधानिकता निर्धारित करते हैं।
(D) संसद के विचार के लिए नए विधान का मसौदा तैयार करते हैं।

264. मार्क्सवादी दृष्टिकोण राजनीतिक परिघटनाओं का विश्लेषण मुख्य रूप से किसके माध्यम से करता है?
(A) व्यक्तिगत मनोविज्ञान
(B) राष्ट्रीय पहचान
(C) वर्ग संघर्ष
(D) संस्थागत कार्य

265. आधुनिक तुलनात्मक राजनीति की 'प्रकृति' को पारंपरिक दृष्टिकोण से क्या अलग करता है?
(A) व्याख्या के बजाय निर्धारण पर ध्यान केंद्रित करना।
(B) तुलना के बजाय एकल-देशीय अध्ययनों पर ध्यान केंद्रित करना।
(C) आनुभविक विश्लेषण और सिद्धांत-निर्माण के प्रति प्रतिबद्धता।
(D) अपने दायरे को पश्चिमी यूरोप तक सीमित रखना।

266. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।
अभिकथन (A): संसदीय प्रणाली में, सरकार अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से अपदस्थ हो सकती है।
कारण (R): कार्यपालिका अपनी वैधता विधायिका के विश्वास से प्राप्त करती है।
(A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(D) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

Downloaded from www.pdf.tube

(A) एक ऐसी व्यवस्था जिसमें एक निर्वाचित राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल का नेतृत्व करने वाला प्रधानमंत्री होता है।
(B) एक ऐसी व्यवस्था जहाँ राष्ट्रपति सभी कार्यकारी और प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग करता है।
(C) एक ऐसी व्यवस्था जहाँ प्रधानमंत्री पूर्णतः निर्वाचित संसद के प्रति उत्तरदायी होता है।
(D) एक ऐसी व्यवस्था जहाँ एक औपचारिक सम्राट राज्य के प्रतीकात्मक प्रमुख के रूप में कार्य करता है।

291. 'राजनीतिक समाजीकरण' प्रक्रिया का केंद्रीय केंद्र क्या है?
(A) विधान का पारित होना।
(B) अदालती मामलों का अधिनिर्णयन।
(C) राजनीतिक विश्वासों और मूल्यों का अर्जन।
(D) विदेश नीति का संचालन।

292. मार्क्सवादी दृष्टिकोण इतिहास को किसके द्वारा परिभाषित देखता है?
(A) प्रभावी राजनीतिक संस्कृति
(B) सरकार की प्रणाली
(C) राजनीतिक विकास का स्तर
(D) उत्पादन की विधि

293. पारंपरिक दृष्टिकोण की परिभाषित विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है?
(A) यह अत्यधिक मात्रात्मक था।
(B) यह गैर-पश्चिमी देशों पर केंद्रित था।
(C) यह आदर्शात्मक और वर्णनात्मक था।
(D) इसने राजनीतिक व्यवहार पर जोर दिया।

294. व्यवस्था विश्लेषण में एक मुख्य अवधारणा यह है कि व्यवस्था को तनाव का सामना करना चाहिए ताकि:
(A) आदर्श स्थिति प्राप्त की जा सके।
(B) समय के साथ अस्तित्व बनाए रखा जा सके।
(C) अपने पड़ोसियों को निर्बल किया जा सके।
(D) सामाजिक वर्गों को समाप्त किया जा सके।

295. नीचे दो कथन दिए गए हैं:
कथन I: न्यायिक समीक्षा विधि के शासन के प्रति प्रतिबद्ध प्रणालियों की एक पहचान है।
कथन II: यह न्यायपालिका को विधायिका और कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने की अनुमति देती है।
(A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं।
(C) कथन I सत्य है, लेकिन कथन II असत्य है।
(D) कथन I असत्य है, लेकिन कथन II सत्य है।

296. लुसियन पाई ने राजनीतिक विकास को व्यवस्था की किस प्रतिक्रिया के संदर्भ में वर्णित किया?
(A) व्यवस्थागत संकट
(B) अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ
(C) आर्थिक चक्र
(D) अभिजन प्राथमिकताएँ

297. निम्नलिखित में से कौन सा 'राजनीतिक संचार' का सबसे उपयुक्त उदाहरण है?
(A) एक बच्चा अपने माता-पिता से राजनीति के बारे में सीख रहा है।
(B) एक न्यायालय प्रतिवादी को दोषी पा रहा है।
(C) एक राष्ट्रपति द्वारा दूरदर्शन पर प्रसारित राष्ट्रीय संबोधन।
(D) एक विधायिका द्वारा बजट पारित किया जाना।

298. अभिजन सिद्धांत में गेटानो मोस्का का मुख्य योगदान किसका विश्लेषण था?
(A) 'शासक वर्ग' की अपरिहार्यता।
(B) अभिजनों के मनोवैज्ञानिक लक्षण।
(C) सैन्य-औद्योगिक परिसर की भूमिका।
(D) संगठनों की अल्पतांत्रिक बनने की प्रवृत्ति।

299. तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य में, सरकार का प्रमुख किसके लिए उत्तरदायी है?
(A) औपचारिक कर्तव्य और राज्य का प्रतिनिधित्व।
(B) उच्चतम न्यायालय की अध्यक्षता करना।
(C) विपक्षी दल का नेतृत्व करना।
(D) सरकार का दैनिक कामकाज चलाना।

300. सरकारों को क्या करना चाहिए, इसके अध्ययन से हटकर वे वास्तव में क्या करती हैं, इसके अध्ययन की ओर बदलाव किसकी विशेषता है?
(A) पारंपरिक दृष्टिकोण
(B) व्यवहारवादी क्रांति
(C) दार्शनिक दृष्टिकोण
(D) ऐतिहासिक दृष्टिकोण

www.nodia.in
NODIA

(A) कार्ल मार्क्स
(B) गैब्रियल आलमंड
(C) डेविड ईस्टन
(D) रॉबर्ट डहल

278. सरकारी अंगों के बीच संबंध 'शक्तियों के पृथक्करण' पर आधारित है:
(A) यूनाइटेड किंगडम में
(B) संयुक्त राज्य अमेरिका में
(C) न्यूज़ीलैंड में
(D) स्वीडन में

279. राजनीतिक मूल्य एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को कैसे हस्तांतरित किए जाते हैं, इसका अध्ययन है:
(A) राजनीतिक संचार
(B) राजनीतिक आधुनिकीकरण
(C) राजनीतिक समाजीकरण
(D) राजनीतिक विकास

280. रॉबर्ट मिचल्स की पुस्तक "पॉलिटिकल पार्टीज" का केंद्रीय तर्क किसमें सन्निहित है?
(A) अल्पतंत्र का लौह नियम
(B) अभिजनों का संचलन
(C) शक्ति अभिजन
(D) नागरिक संस्कृति

281. उत्तर-व्यवहारवादी क्रांति किसकी उपेक्षा के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया थी?
(A) वैज्ञानिक पद्धति
(B) मात्रात्मक विश्लेषण
(C) मूल्य और सामाजिक प्रासंगिकता
(D) आनुभविक अनुसंधान

282. तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य में, विधायिका का एक प्रमुख कार्य क्या है?
(A) जनता का प्रतिनिधित्व करना और कानून बनाना
(B) कानूनों को लागू करना
(C) कानूनी विवादों का निर्णय करना
(D) सशस्त्र बलों की कमान संभालना

283. राजनीतिक विकास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. इसमें व्यवस्था की क्षमता में वृद्धि शामिल है।
2. यह समानता, विभेदीकरण और क्षमता से जुड़ा हुआ है।
3. प्रारंभिक सिद्धांतों ने अक्सर इसे पश्चिमीकरण के समान माना।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3

284. 'जनसंचार माध्यम' किस राजनीतिक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण घटक है?
(A) नियम अधिनिर्णयन
(B) राजनीतिक संचार
(C) न्यायिक समीक्षा
(D) मंत्रिमंडल गठन

285. गेटानो मोस्का की 'शासक वर्ग' की अवधारणा प्रतिपादित करती है कि प्रत्येक समाज में है:
(A) बुर्जुआ और सर्वहारा के बीच संघर्ष।
(B) 'शेर' और 'लोमड़ी' अभिजनों के बीच संचलन।
(C) एक वर्ग जो शासन करता है और एक वर्ग जिस पर शासन किया जाता है।
(D) विशिष्ट क्षेत्रों से बना एक एकीकृत शक्ति अभिजन।

286. निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है?
(A) विधायिका - नियम निर्माण
(B) कार्यपालिका - नियम अनुप्रयोग
(C) न्यायपालिका - नियम अधिनिर्णयन
(D) नौकरशाही - हित समूहन

287. संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण किसके लिए सबसे उपयुक्त है?
(A) यह समझना कि विभिन्न संरचनाएं समान कार्य कैसे निष्पादित करती हैं।
(B) किसी एकल राष्ट्र का विस्तृत ऐतिहासिक विवरण प्रदान करना।
(C) राजनीतिक नेताओं की मनोवैज्ञानिक प्रेरणाओं का विश्लेषण करना।
(D) सरकार के आदर्श रूप को निर्धारित करना।

288. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है।
अभिकथन (A): अभिजनवादी सिद्धांत लोकतंत्र की 'जनता के शासन' के रूप में आलोचना करता है।
कारण (R): यह तर्क देता है कि किसी भी बड़े समाज में शक्ति का प्रयोग अल्पसंख्यक द्वारा किया जाता है।
(A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(D) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

289. तुलनात्मक राजनीति के 'दायरे' में निम्नलिखित में से किसे छोड़कर सभी शामिल हैं?
(A) राजनीतिक संस्थान
(B) राज्यों के बीच राजनयिक संवाद
(C) राजनीतिक व्यवहार
(D) सार्वजनिक नीतियां

290. अर्ध-राष्ट्रपति प्रणाली में, जैसे कि फ्रांस की, वहाँ है:

Click Here to Buy book on Amazon

10. (A) कानूनों की व्याख्या करना और विवादों का निपटारा करना।
किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में न्यायपालिका का मुख्य उत्तरदायित्व कानूनों की व्याख्या करना और विवादों का विधिसम्मत निपटारा करना है। यह अंग संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करता है और यह सुनिश्चित करता है कि सरकार के अन्य अंग अपनी संवैधानिक सीमाओं का उल्लंघन न करें। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना और निष्पक्ष न्याय प्रदान करना इसकी स्वायत्तता का आधार है, जो कानून के शासन को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है।

11. (A) केवल 1 और 2
राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया मुख्य रूप से संस्कृति के धर्मनिरपेक्षीकरण और राजनीतिक संस्थानों के भीतर संरचनात्मक विभेदीकरण द्वारा विशेषीकृत होती है। इसमें पारंपरिक निष्ठाओं का स्थान तर्कसंगत-कानूनी प्राधिकार ले लेता है और राजनीतिक भूमिकाओं में विशिष्टीकरण आता है। हालाँकि, यह आवश्यक नहीं है कि आधुनिकीकरण हमेशा स्थिर लोकतांत्रिक परिणामों की ओर ले जाए; कभी-कभी संस्थागत विकास के अभाव में यह राजनीतिक अस्थिरता या पतन का कारण भी बन सकता है।

12. (B) राजनीति के प्रति किसी जनसंख्या की सामूहिक अभिवृत्तियाँ, विश्वास और मूल्य।
राजनीतिक संस्कृति शब्द का तात्पर्य उन व्यक्तिपरक अभिवृत्तियों, विश्वासों, मूल्यों और कौशलों से है जो किसी समाज की राजनीतिक व्यवस्था को आधार प्रदान करते हैं। यह नागरिकों के राजनीतिक व्यवहार को गहराई से प्रभावित करती है और यह निर्धारित करती है कि वे सत्ता को किस प्रकार देखते हैं और उसमें कैसे भाग लेते हैं। यह अवधारणा राजनीति के अध्ययन में मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्रीय आयामों को जोड़कर शासन की स्थिरता को समझने में मदद करती है।

13. (C) राजनीतिक वर्ग और जनसमूह।
गेटानो मोस्का ने अपनी प्रसिद्ध कृति 'द रूलिंग क्लास' में तर्क दिया कि सभी समाज दो वर्गों में विभाजित होते हैं: एक अल्पसंख्यक वर्ग जो शासन करता है और एक बहुसंख्यक जनसमूह जिस पर शासन किया जाता है। शासक वर्ग अपनी संगठनात्मक क्षमता और बौद्धिक श्रेष्ठता के कारण सत्ता पर अपना नियंत्रण बनाए रखता है। मोस्का के अनुसार, लोकतंत्र में भी वास्तव में शक्ति एक संगठित अल्पसंख्यक राजनीतिक वर्ग के हाथों में ही केंद्रित रहती है।

14. (A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तुलनात्मक राजनीति के दायरे में व्यापक विस्तार हुआ क्योंकि वि-औपनिवेशीकरण के कारण एशिया और अफ्रीका में अनेक नए स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ। इन नए राज्यों की विविध राजनीतिक प्रणालियों और चुनौतियों ने विद्वानों को केवल पश्चिमी मॉडलों से आगे बढ़कर अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया। इस प्रक्रिया ने तुलनात्मक विश्लेषण के लिए नए केंद्र प्रदान किए, जिससे राजनीतिक विकास और आधुनिकीकरण जैसे नए सिद्धांतों का जन्म हुआ।

15. (A) राज्य शासक वर्ग के हितों के प्रबंधन का एक साधन है।
मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अनुसार, राज्य समाज में एक तटस्थ मध्यस्थ नहीं है, बल्कि यह आर्थिक रूप से प्रभावी शासक वर्ग के हितों की रक्षा करने वाला एक यंत्र है। राज्य का अस्तित्व वर्ग संघर्ष के कारण होता है और इसका मुख्य कार्य उत्पादन की मौजूदा पद्धति और निजी संपत्ति की रक्षा करना है। पूंजीवादी व्यवस्था में राज्य बुर्जुआ वर्ग की सत्ता को बनाए रखने और सर्वहारा वर्ग के शोषण को वैध बनाने का कार्य करता है।

NODIA

16. (B) एक अलग, लोकप्रिय जनादेश और कार्यालय का एक निश्चित कार्यकाल।
सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली में कार्यपालिका की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक अलग जनादेश के माध्यम से किया जाता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल संवैधानिक रूप से निश्चित होता है और वह अपनी नीतियों के लिए विधायिका के विश्वास पर निर्भर नहीं होता है। इसमें शक्तियों का स्पष्ट पृथक्करण होता है, जहाँ राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष और सरकार के प्रमुख दोनों की भूमिकाएं एक साथ निभाता है।

17. (B) हित प्रकटीकरण
गैब्रियल आलमंड के संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक ढांचे में हित प्रकटीकरण को एक महत्वपूर्ण 'आगत कार्य' माना गया है। यह वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समाज के विभिन्न समूह और व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं, मांगों और दावों को राजनीतिक व्यवस्था के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। यह कार्य अक्सर दबाव समूहों और नागरिक संगठनों द्वारा किया जाता है, जो जनता की इच्छाओं को नीति निर्माताओं तक पहुँचाने में एक सेतु के रूप में कार्य करते हैं।

18. (A) रॉबर्ट मिचल्स
'अल्पतंत्र का लौह नियम' का प्रतिपादन रॉबर्ट मिचल्स ने अपनी पुस्तक 'पॉलिटिकल पार्टीज' में किया था। उनका मुख्य तर्क यह था कि किसी भी संगठन का स्वरूप चाहे कितना भी लोकतांत्रिक क्यों न हो, उसमें अंततः सत्ता का केंद्रीकरण एक छोटे से नेतृत्व समूह के हाथों में हो जाता है। संगठनात्मक जटिलता और नेतृत्व की विशेषज्ञता की आवश्यकता के कारण, बहुसंख्यक सदस्य निष्क्रिय हो जाते हैं और संगठन धीरे-धीरे अल्पतांत्रिक बन जाता है।

19. (C) आनुवंशिक प्रवृत्ति
राजनीतिक समाजीकरण एक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, न कि कोई जैविक या आनुवंशिक परिघटना। इसके मुख्य अभिकर्ताओं में परिवार, शैक्षणिक संस्थान, मित्र समूह और जनसंचार माध्यम शामिल हैं, जो व्यक्ति के राजनीतिक मूल्यों और विश्वासों को आकार देते हैं। आनुवंशिक प्रवृत्तियाँ शारीरिक लक्षणों को निर्धारित कर सकती हैं, लेकिन राजनीतिक विचारधारा और अभिवृत्तियाँ पूरी तरह से सामाजिक वातावरण और अनुभवों के माध्यम से सीखी जाती हैं, जो व्यक्ति के नागरिक जीवन को प्रभावित करती हैं।

उत्तर (व्याख्या सहित)

1. (B) घरेलू राजनीतिक प्रणालियों का आनुभविक अध्ययन और तुलना।
तुलनात्मक राजनीति मुख्य रूप से विश्व के विभिन्न देशों की घरेलू राजनीतिक प्रणालियों के आनुभविक अध्ययन और उनके बीच विद्यमान समानता एवं अंतर की खोज से संबंधित है। यह विषय केवल औपचारिक संस्थाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि राजनीतिक व्यवहार, प्रक्रियाओं और शक्ति संरचनाओं का सूक्ष्म विश्लेषण करता है। इसका मुख्य उद्देश्य सिद्धांतों का निर्माण करना और वैश्विक स्तर पर विविध शासन पद्धतियों की जटिल कार्यप्रणाली को गहराई से समझना है।

2. (A) यह काफी हद तक आदर्शात्मक और वर्णनात्मक था।
तुलनात्मक राजनीति का पारंपरिक दृष्टिकोण मुख्य रूप से वर्णनात्मक और आदर्शात्मक विशेषताओं से युक्त रहा है। यह दृष्टिकोण सरकारी संस्थाओं, जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की औपचारिक-कानूनी संरचनाओं के अध्ययन पर अत्यधिक केंद्रित था। इसमें राजनीति के वास्तविक व्यवहार के स्थान पर 'क्या होना चाहिए' पर अधिक बल दिया जाता था और विश्लेषण का दायरा मुख्य रूप से केवल पश्चिमी यूरोपीय देशों के अनुभवों तक ही सीमित रहता था।

3. (C) राजनीतिक व्यवस्था में आगत।
डेविड ईस्टन के व्यवस्था सिद्धांत के अंतर्गत मांग और समर्थन को राजनीतिक व्यवस्था के आगत के रूप में वर्गीकृत किया गया है। आगत वे तत्व हैं जो बाहरी पर्यावरण से राजनीतिक व्यवस्था में प्रवेश करते हैं और निर्णय लेने की प्रक्रिया को गति प्रदान करते हैं। मांगें जनता की विशिष्ट इच्छाओं को दर्शाती हैं, जबकि समर्थन व्यवस्था के प्रति नागरिकों की निष्ठा और नियमों के पालन के माध्यम से उसकी स्थिरता सुनिश्चित करता है।

4. (D) विधायिका और कार्यपालिका शक्तियों के सख्त पृथक्करण के तहत कार्य करते हैं।
संसदीय शासन प्रणाली की सबसे प्रमुख विशेषता कार्यपालिका और विधायिका के बीच शक्तियों का संलयन है, न कि उनका सख्त पृथक्करण। इस व्यवस्था में कार्यपालिका का जन्म विधायिका के भीतर से ही होता है और वह अपने अस्तित्व के लिए विधायिका के निरंतर विश्वास पर निर्भर रहती है। प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से संसद के निचले सदन के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जो उत्तरदायित्व के लोकतांत्रिक सिद्धांत को सुदृढ़ बनाता है।

5. (C) क्रांति
लुसियन पाई ने राजनीतिक विकास के तीन मुख्य आयामों की पहचान की है, जिन्हें समानता, क्षमता और विभेदीकरण के रूप में जाना जाता है। समानता नागरिक भागीदारी और कानूनों के समान अनुप्रयोग को दर्शाती है। क्षमता का अर्थ सरकार की सार्वजनिक मामलों के प्रबंधन और समस्याओं के समाधान की शक्ति है। विभेदीकरण राजनीतिक भूमिकाओं और संस्थानों के विशिष्टीकरण को दर्शाता है। क्रांति इस त्रि-स्तरीय शास्त्रीय ढांचे का हिस्सा नहीं मानी जाती है।

6. (A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।
राजनीतिक समाजीकरण वह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति समाज में प्रचलित राजनीतिक मूल्यों, विश्वासों और अभिवृत्तियों को ग्रहण करता है। इस प्रक्रिया में परिवार को प्राथमिक अभिकर्ता माना जाता है क्योंकि बच्चा सबसे पहले अपने माता-पिता के माध्यम से राजनीतिक सूचनाएं और दृष्टिकोण प्राप्त करता है। यह प्रक्रिया नागरिक पहचान के निर्माण और राजनीतिक व्यवस्था की स्थिरता एवं निरंतरता बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक और महत्वपूर्ण है।

7. (D) विल्फ्रेडो पेरेटो
अभिजनों के संचलन की अवधारणा इतालवी समाजशास्त्री विल्फ्रेडो पेरेटो द्वारा प्रतिपादित की गई थी। उनका तर्क था कि समाज में शक्ति हमेशा एक छोटे अल्पसंख्यक समूह के पास होती है। इतिहास विभिन्न अभिजन समूहों के बीच सत्ता के निरंतर हस्तांतरण की एक श्रृंखला है। उन्होंने अभिजनों को 'शेर' और 'लोमड़ी' की श्रेणियों में विभाजित किया, जो क्रमशः बल और चतुराई के माध्यम से शासन करने की प्रभावी शैलियों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

8. (A) 1, 2, 4, 3
तुलनात्मक राजनीति का विकास सर्वप्रथम औपचारिक-कानूनी संस्थानों के अध्ययन से प्रारंभ हुआ। इसके पश्चात द्वितीय विश्व युद्ध के बाद व्यवहारवादी क्रांति आई, जिसने व्यक्तिगत राजनीतिक क्रियाओं और आनुभविक शोध पर ध्यान केंद्रित किया। इसके उपरांत उत्तर-व्यवहारवाद का उदय हुआ, जिसने शोध में प्रासंगिकता और सामाजिक कार्रवाई पर बल दिया। अंततः आधुनिक काल में राजनीतिक अर्थव्यवस्था और तर्कसंगत चयन जैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोणों का समावेश हुआ, जिससे यह विषय और अधिक व्यापक हुआ।

9. (C) संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण
गैब्रियल आलमंड द्वारा प्रतिपादित संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण इस विचार पर आधारित है कि प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में कुछ बुनियादी कार्य अनिवार्य रूप से किए जाते हैं। यह दृष्टिकोण उन संरचनाओं की पहचान करता है जो हित प्रकटीकरण और हित समूहन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को निष्पादित करती हैं। इसका उद्देश्य यह समझना है कि विभिन्न संस्कृतियों में अलग-अलग संस्थाएं किस प्रकार व्यवस्था की स्थिरता, अनुकूलन और निरंतरता बनाए रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती हैं।

Downloaded from www.pdf.tube

अभिकथन (A): संरचनात्मक-प्रकार्यवाद विविध प्रणालियों की तुलना करने की अनुमति देता है।
कारण (R): यह मानता है कि सभी प्रणालियाँ अस्तित्व बनाए रखने के लिए कुछ सार्वभौमिक कार्य करती हैं।
(A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(D) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

246. व्यवस्था विश्लेषण मॉडल में, निम्नलिखित में से कौन सा 'समर्थन' आगत का एक उदाहरण है?
(A) करों का भुगतान और विधि का पालन।
(B) कर कटौती के लिए एक अनुरोध।
(C) स्वच्छ वायु की मांग को लेकर किया गया विरोध प्रदर्शन।
(D) विधायिका द्वारा पारित एक नया कानून।

247. राष्ट्रपति प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका के बीच प्राथमिक अंतर क्या है?
(A) विधायिका कार्यपालिका से अधिक शक्तिशाली होती है।
(B) कार्यपालिका विधायिका की एक समिति होती है।
(C) सभी न्यायिक नियुक्तियों में विधायिका का अंतिम निर्णय होता है।
(D) उनके पास वैधता के पृथक स्रोत और स्वतंत्रता होती है।

248. राजनीतिक संस्कृति का अध्ययन मुख्य रूप से जांच करता है:
(A) राजनीतिक व्यवस्था के औपचारिक, लिखित नियम।
(B) किसी देश का आर्थिक निष्पादन।
(C) राजनीति के प्रति रखे गए व्यक्तिपरक अभिवृत्ति, विश्वास और मूल्य।
(D) राष्ट्र की सरकार का ऐतिहासिक विकास।

249. निम्नलिखित में से कौन 'लोकतंत्र के अभिजनवादी सिद्धांत' का सबसे अच्छा वर्णन करता है?
(A) एक सिद्धांत जो लोकतंत्र को सत्ता के लिए अभिजनों के बीच एक प्रतिस्पर्धी संघर्ष के रूप में परिभाषित करता है।
(B) एक सिद्धांत जो लोकतंत्र को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में देखता है जहाँ जनसमूह सीधे शासन करता है।
(C) एक सिद्धांत जो वंशानुगत अभिजात वर्ग द्वारा शासन की वकालत करता है।
(D) एक सिद्धांत जो तर्क देता है कि शक्ति अनेक समूहों के बीच व्यापक रूप से वितरित है।

250. सूची I को सूची II के साथ सुमेलित करें।
सूची I: (दृष्टिकोण)
P. पारंपरिक दृष्टिकोण
Q. व्यवस्था दृष्टिकोण
R. संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण
S. मार्क्सवादी दृष्टिकोण
सूची II: (मूल अवधारणा)
1. आगत, निर्गत, फीडबैक
2. आधार और अधिसंरचना
3. औपचारिक-कानूनी संस्थान
4. आगत-निर्गत कार्य
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:
(A) P-1, Q-3, R-4, S-2
(B) P-3, Q-1, R-4, S-2
(C) P-3, Q-4, R-1, S-2
(D) P-1, Q-4, R-3, S-2

251. राजनीति विज्ञान में 'व्यवहारवादी क्रांति' ने किस पर जोर दिया?
(A) शास्त्रीय राजनीतिक दर्शन की ओर वापसी।
(B) औपचारिक संविधानों और कानूनों का अध्ययन।
(C) अवलोकन योग्य राजनीतिक व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन।
(D) अंतर्राष्ट्रीय कानून और कूटनीति पर ध्यान।

252. 'विधायिका का पतन' सिद्धांत तर्क देता है कि आधुनिक शासन में:
(A) न्यायपालिका सबसे शक्तिशाली शाखा बन गई है।
(B) शक्ति विधायिका से कार्यपालिका और नौकरशाही की ओर स्थानांतरित हो गई है।
(C) विश्व स्तर पर विधायी निकायों की संख्या कम हो रही है।
(D) नागरिक अब अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों पर विश्वास नहीं करते।

253. राजनीतिक आधुनिकीकरण सामाजिक परिवर्तन की वह प्रक्रिया है जो:
(A) राजनीति और सरकार के पारंपरिक स्वरूप से आधुनिक स्वरूप की ओर ले जाती है।
(B) कृषि समाज से औद्योगिक समाज की ओर ले जाती है।
(C) लोकतांत्रिक शासन से सत्तावादी शासन की ओर ले जाती है।
(D) सरकार की स्थानीय प्रणाली से राष्ट्रीय प्रणाली की ओर ले जाती है।

254. निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक समाजीकरण का अभिकर्ता नहीं है?
(A) परिवार
(B) विद्यालय
(C) जनसंचार माध्यम
(D) न्यायपालिका

255. "अल्पतंत्र का लौह नियम" यह निष्कर्ष निकालता है कि:
(A) सरकार के सभी रूप समान रूप से लोकतांत्रिक हैं।
(B) बड़े पैमाने के संगठन से कुछ लोगों का शासन होता है, जिससे सहभागिता कठिन हो जाती है।
(C) पूंजीवाद स्वाभाविक रूप से अल्पतांत्रिक है, जबकि

NODIA

20. (A) P-2, Q-1, R-4, S-3
तुलनात्मक राजनीति की विभिन्न अवधारणाएं उनके विशिष्ट प्रतिपादकों से जुड़ी हैं। डेविड ईस्टन ने राजनीतिक व्यवस्था के विश्लेषण के लिए 'व्यवस्था सिद्धांत' प्रस्तुत किया, जबकि गैब्रियल आलमंड ने 'संरचनात्मक प्रकार्यवाद' का ढांचा विकसित किया। लुसियन पाई ने विकासशील देशों के संदर्भ में 'राजनीतिक विकास के संकटों' की पहचान की और कार्ल मार्क्स ने समाज के विश्लेषण के लिए 'आधार और अधिसंरचना' का सिद्धांत दिया। ये सभी सिद्धांत राजनीति को समझने के लिए विविध दृष्टिकोण प्रदान करते हैं।

21. (C) व्यवहारवादी क्रांति
तुलनात्मक राजनीति में वर्णनात्मक और कानूनी-संस्थागत अध्ययन से हटकर अधिक वैज्ञानिक और आनुभविक विश्लेषण की ओर बदलाव को 'व्यवहारवादी क्रांति' के रूप में जाना जाता है। इस आंदोलन ने औपचारिक संस्थाओं के स्थान पर राजनीतिक अभिनेताओं, समूहों और व्यक्तियों के वास्तविक व्यवहार के अध्ययन पर बल दिया। इसका उद्देश्य राजनीति विज्ञान को एक अधिक सटीक और भविष्यवाणी करने योग्य अनुशासन बनाना था, जिसमें मात्रात्मक डेटा और सांख्यिकीय विधियों का व्यापक प्रयोग किया जाने लगा।

22. (B) प्रजाभावी संस्कृति
प्रजाभावी राजनीतिक संस्कृति में नागरिक राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था और सरकार द्वारा किए गए निर्णयों के प्रति जागरूक तो होते हैं, लेकिन वे स्वयं को एक निष्क्रिय प्रजा के रूप में देखते हैं। उनकी अभिवृत्ति मुख्य रूप से सरकार के 'निर्गत' कार्यों, जैसे कानून और नीतियों के पालन तक सीमित रहती है। इस संस्कृति में नागरिकों के पास व्यवस्था को प्रभावित करने या नीति निर्माण प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने की प्रेरणा और क्षमता का अभाव होता है।

23. (D) दूसरा सदन अक्सर उप-राष्ट्रीय इकाइयों को प्रतिनिधित्व प्रदान करता है।
द्विसदनीय विधायिका की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसका दूसरा सदन अक्सर संघ की घटक इकाइयों या राज्यों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। यह व्यवस्था शक्तियों के संतुलन को बनाए रखने और जल्दबाजी में किए गए विधायी निर्णयों को रोकने में मदद करती है। विशेष रूप से संघीय राज्यों में, जैसे भारत और अमेरिका में, दूसरा सदन क्षेत्रीय हितों की रक्षा करने और राष्ट्रीय विधान प्रक्रिया में विविधता सुनिश्चित करने में सहायक होता है।

24. (A) राजनीतिक भूमिकाओं और संस्थानों का विशिष्टीकरण।
राजनीतिक आधुनिकीकरण के संदर्भ में 'विभेदीकरण' का अर्थ राजनीतिक व्यवस्था के भीतर विभिन्न कार्यों के लिए विशिष्ट संरचनाओं और भूमिकाओं का उदय है। जैसे-जैसे समाज आधुनिक होता है, प्रशासनिक, विधायी और न्यायिक कार्य अलग-अलग संस्थानों द्वारा किए जाने लगते हैं। यह प्रक्रिया शासन की क्षमता और दक्षता में वृद्धि करती है, क्योंकि प्रत्येक अंग अपने विशिष्ट कार्य में विशेषज्ञता हासिल कर लेता है, जिससे जटिल सामाजिक समस्याओं का समाधान सरल हो जाता है।

25. (C) मतों के लिए प्रतिस्पर्धी संघर्ष के माध्यम से नेताओं को चुनने की एक प्रक्रियात्मक विधि।
लोकतंत्र का अभिजनवादी सिद्धांत, जिसका समर्थन जोसेफ शुम्पेटर जैसे विद्वानों ने किया, लोकतंत्र को मुख्य रूप से एक प्रक्रियात्मक विधि के रूप में देखता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार, जनता स्वयं शासन नहीं करती, बल्कि वह चुनावों के माध्यम से प्रतिस्पर्धी अभिजन समूहों में से अपने शासकों का चयन करती है। यहाँ लोकतंत्र का अर्थ नीतियों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण के स्थान पर नेताओं के बीच प्रतिस्पर्धा के माध्यम से सत्ता के हस्तांतरण की एक शांतिपूर्ण व्यवस्था है।

26. (A) नियम अनुप्रयोग
संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक विश्लेषण में 'निर्गत कार्यों' का तात्पर्य उन गतिविधियों से है जो राजनीतिक व्यवस्था द्वारा लिए गए निर्णयों को लागू करने से संबंधित हैं। नियम अनुप्रयोग, जिसे सामान्यतः कार्यपालिका और नौकरशाही द्वारा निष्पादित किया जाता है, एक प्रमुख निर्गत कार्य है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि विधायिका द्वारा बनाए गए कानून और नीतियां समाज में प्रभावी ढंग से क्रियान्वित हों। अन्य निर्गत कार्यों में नियम निर्माण और नियम अधिनिर्णयन शामिल हैं, जो व्यवस्था की स्थिरता बनाए रखते हैं।

27. (D) कानूनी और नैतिक सिद्धांत जो शासक वर्ग की शक्ति को न्यायोचित ठहराते हैं।
गेटानो मोस्का ने 'राजनीतिक सूत्र' की अवधारणा का उपयोग उन मान्यताओं, सिद्धांतों और विचारधाराओं को समझाने के लिए किया जो किसी शासक वर्ग के प्रभुत्व को नैतिक और कानूनी आधार प्रदान करते हैं। उनका तर्क था कि कोई भी अभिजन केवल बल के आधार पर शासन नहीं कर सकता; उसे अपनी सत्ता की स्वीकार्यता के लिए समाज में प्रचलित विश्वासों का सहारा लेना पड़ता है। यह सूत्र शासकों को वैधता प्रदान करता है और जनता को आज्ञाकारी बनाए रखने में मदद करता है।

28. (A) केवल 1 और 2
तुलनात्मक राजनीति का पारंपरिक दृष्टिकोण मुख्य रूप से औपचारिक-कानूनी संस्थाओं, जैसे संविधान, विधायिका और कार्यपालिका के अध्ययन तक सीमित था। यह अक्सर आदर्शात्मक प्रकृति का था, जिसका उद्देश्य सरकार के 'सर्वोत्तम' स्वरूप को निर्धारित करना था। इसकी एक बड़ी सीमा यह थी कि यह मुख्य रूप से पश्चिमी लोकतांत्रिक देशों के अनुभवों पर आधारित था और इसने गैर-पश्चिमी या विकासशील देशों की राजनीतिक वास्तविकताओं और प्रक्रियाओं की लंबे समय तक उपेक्षा की, जिससे यह संकुचित बना रहा।

29. (C) संसदीय प्रणाली
संसदीय शासन प्रणाली की पहचान कार्यपालिका और विधायिका के बीच 'शक्तियों के संलयन' से होती है। इस व्यवस्था में कार्यपालिका के सदस्य अनिवार्य रूप से

Click Here to Buy book on Amazon

विधायिका के भी सदस्य होते हैं और वे अपने पद पर बने रहने के लिए विधायिका के बहुमत के विश्वास पर निर्भर करते हैं। यह निरंतर सहयोग और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करता है, जहाँ सरकार अपनी नीतियों और कार्यों के लिए सीधे तौर पर जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रति जवाबदेह बनी रहती है।

30. (A) जनसंख्या शासन करने के लिए सरकार के उचित अधिकार पर सवाल उठाती है।
राजनीतिक विकास के दौरान 'वैधता का संकट' तब उत्पन्न होता है जब समाज का एक बड़ा हिस्सा सरकार के शासन करने के नैतिक और कानूनी अधिकार को स्वीकार करने से इनकार कर देता है। यह स्थिति अक्सर तब आती है जब सरकार नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा करने में विफल रहती है या जब सत्ता के हस्तांतरण की प्रक्रिया को अनुचित माना जाता है। वैधता की कमी राजनीतिक अस्थिरता, आंदोलनों और कभी-कभी शासन के पतन की ओर ले जा सकती है।

31. (D) राजनीतिक संचार
कार्ल डॉयच तुलनात्मक राजनीति में 'राजनीतिक संचार' दृष्टिकोण के प्रमुख प्रणेता माने जाते हैं। उन्होंने राजनीतिक व्यवस्था को सूचनाओं और संदेशों के प्रवाह के तंत्र के रूप में देखा। उनका तर्क था कि किसी भी सरकार की प्रभावशीलता और स्थिरता उसके भीतर संचार के चैनलों की दक्षता पर निर्भर करती है। उन्होंने 'तंत्रिका जाल' जैसे मॉडल का उपयोग करते हुए यह समझाया कि कैसे सूचना का प्रसंस्करण राजनीतिक निर्णयों और सामाजिक एकीकरण को आकार देता है।

32. (B) सी. राइट मिल्स
अमेरिकी समाजशास्त्री सी. राइट मिल्स ने 'शक्ति अभिजन' की अवधारणा प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने तर्क दिया कि आधुनिक औद्योगिक समाज में सत्ता तीन परस्पर जुड़े क्षेत्रों के नेताओं के पास होती है: आर्थिक (कॉर्पोरेट), राजनीतिक और सैन्य। उनके अनुसार, ये तीनों समूह एक एकीकृत वर्ग के रूप में कार्य करते हैं जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय निर्णयों को नियंत्रित करते हैं। यह विचार इस धारणा को चुनौती देता है कि लोकतंत्र में शक्ति व्यापक रूप से जनता के बीच बिखरी हुई होती है।

33. (A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं और कथन II, कथन I की सही व्याख्या है।
न्यायिक समीक्षा की शक्ति न्यायपालिका को विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों और कार्यपालिका के निर्णयों की संवैधानिक वैधता की जाँच करने का अधिकार देती है। यदि कोई कानून या कार्य संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो अदालतें उसे शून्य घोषित कर सकती हैं। यह शक्ति शक्तियों के संतुलन को बनाए रखने और सरकार की मनमानी को रोकने में एक महत्वपूर्ण उपकरण है, जो अंततः व्यक्तिगत स्वतंत्रता और संविधान की सर्वोच्चता की रक्षा सुनिश्चित करती है।

34. (A) एक ही सदन या कक्ष से बनी होती है।
एकसदनीय विधायिका वह विधायी प्रणाली है जिसमें केवल एक सदन या कक्ष होता है। इस प्रकार की व्यवस्था अक्सर छोटे और एकात्मक राज्यों में पाई जाती है जहाँ जनसंख्या और क्षेत्रीय विविधता अपेक्षाकृत कम होती है। एकसदनीय प्रणाली का मुख्य लाभ कानून निर्माण प्रक्रिया की तीव्र गति और कम प्रशासनिक व्यय है। इसमें शक्तियों का कोई आंतरिक विभाजन नहीं होता, जिससे विधायी निर्णय लेने में स्पष्टता और सरलता बनी रहती है, हालांकि इसमें पुनरीक्षण की कमी हो सकती है।

35. (C) एक राजनीतिक दल जो विभिन्न समूहों की मांगों को समन्वित करने वाला एक मंच विकसित करता है।
हित समूहन वह प्रक्रिया है जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों की विविध और कभी-कभी विरोधाभासी मांगों को एकीकृत करके सुसंगत नीतिगत विकल्पों में बदला जाता है। राजनीतिक दल इस कार्य में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि वे विभिन्न दबाव समूहों के हितों के बीच तालमेल बिठाते हैं और उन्हें एक व्यापक चुनावी कार्यक्रम या सरकारी नीति के रूप में प्रस्तुत करते हैं। यह कार्य राजनीतिक व्यवस्था की कार्यक्षमता और स्थिरता बनाए रखने के लिए अनिवार्य है।

36. (A) 1, 3, 2
शास्त्रीय अभिजन सिद्धांतकारों के कार्यों का प्रकाशन क्रम उनके विचारों के विकास को दर्शाता है। गेटानो मोस्का ने सबसे पहले 'द रुलिंग क्लास' के माध्यम से संगठित अल्पसंख्यक के शासन का विचार दिया। इसके बाद रॉबर्ट मिचल्स ने 'अल्पतंत्र का लौह नियम' प्रतिपादित करते हुए संगठनों के भीतर शक्ति के केंद्रीकरण को स्पष्ट किया। विल्फ्रेडो पेरेटो ने अपने समाजशास्त्रीय विश्लेषण में अभिजनों के संचलन और उनके मनोवैज्ञानिक गुणों पर विस्तार से चर्चा की, जिससे यह सिद्धांत और अधिक समृद्ध हुआ।

37. (C) व्यवस्था के निष्पादन के बारे में जानकारी वापस उसे प्रेषित की जाती है।
डेविड ईस्टन के व्यवस्था विश्लेषण मॉडल में प्रतिपुष्टि (फीडबैक) एक महत्वपूर्ण तंत्र है। यह वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों और नीतियों (निर्गत) के प्रभाव के बारे में जानकारी वापस आगत के रूप में व्यवस्था में पहुँचती है। यह व्यवस्था को अपनी भविष्य की नीतियों को समायोजित करने और पर्यावरण की बदलती मांगों के अनुरूप ढलने में मदद करता है। प्रतिपुष्टि तंत्र राजनीतिक व्यवस्था की निरंतरता और आत्म-सुधार की क्षमता सुनिश्चित करता है।

38. (B) राजनीतिक प्रणालियों के बीच और उनके भीतर समानताएं और अंतर।
तुलनात्मक राजनीति का मुख्य उद्देश्य विभिन्न देशों की राजनीतिक प्रणालियों का व्यवस्थित अध्ययन करना है ताकि उनके बीच विद्यमान समानताओं और विविधताओं को समझा जा सके। यह विषय केवल सरकारों के ढांचे तक सीमित नहीं है, बल्कि यह राजनीतिक प्रक्रियाओं, संस्थानों, व्यवहार और शासन के परिणामों का विश्लेषण करता है। तुलना के माध्यम से विद्वान सामान्य सिद्धांतों को विकसित करने और यह समझने का प्रयास करते हैं कि विभिन्न राजनीतिक वातावरणों में सत्ता का प्रयोग कैसे किया जाता है।

NODIA

39. (D) यदि संस्थागत विकास अपर्याप्त है, तो आधुनिकीकरण से राजनीतिक पतन होता है।
सैमुअल हंटिंगटन ने तर्क दिया कि राजनीतिक आधुनिकीकरण, जिसमें बढ़ती भागीदारी और सामाजिक गतिशीलता शामिल है, हमेशा स्थिरता नहीं लाता है। यदि किसी समाज में राजनीतिक संस्थाओं का विकास (संस्थाकरण) सामाजिक मांगों और भागीदारी की गति से पीछे रह जाता है, तो इसके परिणामस्वरूप राजनीतिक अस्थिरता, अव्यवस्था और 'राजनीतिक पतन' हो सकता है। अतः, सफल आधुनिकीकरण के लिए मजबूत और प्रभावी संस्थानों का निर्माण अनिवार्य है जो बढ़ती जनभागीदारी को व्यवस्थित रूप से आत्मसात कर सकें।

40. (A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।
तुलनात्मक राजनीति के पारंपरिक दृष्टिकोण की अक्सर 'यूरोप-केंद्रित' होने के लिए आलोचना की जाती है क्योंकि इसका अध्ययन मुख्य रूप से यूरोप और उत्तरी अमेरिका की सरकारों तक सीमित था। यह दृष्टिकोण औपचारिक-कानूनी संरचनाओं, जैसे संविधानों और संप्रभुता के कानूनी पहलुओं पर अत्यधिक केंद्रित था। इसके परिणामस्वरूप, इसने एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के उभरते राज्यों की अद्वितीय राजनीतिक प्रक्रियाओं और अनौपचारिक व्यवहारों की अनदेखी की, जिससे इसका विश्लेषण वैश्विक संदर्भ में अपूर्ण और संकुचित रहा।

41. (D) विशेष रूप से औपचारिक सरकारी संस्थानों पर ध्यान केंद्रित करना।
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आधुनिक तुलनात्मक राजनीति ने अपने स्वरूप में व्यापक परिवर्तन किया। अब यह केवल औपचारिक सरकारी संस्थानों के अध्ययन तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसमें अनौपचारिक प्रक्रियाओं, राजनीतिक व्यवहार और समूहों की भूमिका को भी शामिल किया गया। यह विषय अधिक विश्लेषणात्मक और वैज्ञानिक बनने की ओर बढ़ा, जिसमें सिद्धांतों के निर्माण और वैश्विक स्तर पर विविधता को शामिल करने पर जोर दिया गया। व्यवहारवादी क्रांति ने इसे पारंपरिक कानूनी-संस्थागत सीमाओं से मुक्त कर एक नया आयाम दिया।

42. (B) नागरिकों को राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बहुत कम या बिल्कुल जानकारी नहीं होती है।
संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति उन समाजों की विशेषता है जहाँ नागरिकों में राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था के प्रति जागरूकता का अभाव होता है। ऐसे समाजों में व्यक्ति अक्सर स्थानीय कबीले, धर्म या जातीय समूहों के प्रति अधिक निष्ठा रखते हैं और वे यह नहीं समझते कि केंद्र सरकार उनके जीवन को कैसे प्रभावित कर सकती है। यहाँ राजनीतिक भूमिकाएं विशिष्ट नहीं होतीं और नागरिक स्वयं को राजनीतिक प्रक्रिया के सक्रिय हिस्से के रूप में नहीं देखते, जिससे राष्ट्रीय एकीकरण चुनौतीपूर्ण हो जाता है।

43. (C) अभिजन का संचलन - गेटानो मोस्का
'अभिजन का संचलन' की अवधारणा वास्तव में विल्फ्रेडो पेरेटो से जुड़ी हुई है, न कि गेटानो मोस्का से। पेरेटो ने तर्क दिया था कि इतिहास विभिन्न अभिजन समूहों के बीच सत्ता के निरंतर हस्तांतरण की प्रक्रिया है। दूसरी ओर, गेटानो मोस्का ने 'शासक वर्ग' और 'राजनीतिक सूत्र' के विचारों को विकसित किया। अन्य युग्म सही हैं, जैसे सी. राइट मिल्स ने 'शक्ति अभिजन', रॉबर्ट मिचल्स ने 'अल्पतंत्र का लौह नियम' और डेविड ईस्टन ने 'व्यवस्था विश्लेषण' का सिद्धांत प्रस्तुत किया था।

44. (D) एक औपचारिक सम्राट या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति।
संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका के दो प्रमुख होते हैं: वास्तविक प्रमुख और नाममात्र का प्रमुख। प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करता है और सरकार का नेतृत्व करता है। इसके विपरीत, राष्ट्राध्यक्ष अक्सर एक औपचारिक भूमिका निभाता है, जो या तो एक संवैधानिक सम्राट (जैसे यूनाइटेड किंगडम में) या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति (जैसे भारत में) हो सकता है। राष्ट्राध्यक्ष राज्य की एकता का प्रतीक होता है, जबकि वास्तविक शासन संसद के प्रति उत्तरदायी मंत्रिमंडल द्वारा संचालित होता है।

45. (C) 'आधार', जो उत्पादन की विधि है।
मार्क्सवादी विश्लेषण के अनुसार, समाज की 'अधिसंरचना', जिसमें कानून, राजनीति, धर्म और संस्कृति शामिल हैं, अंततः समाज के आर्थिक 'आधार' द्वारा निर्धारित होती है। आधार में उत्पादन की शक्तियाँ और उत्पादन के संबंध शामिल होते हैं। कार्ल मार्क्स का तर्क था कि समाज का आर्थिक ढांचा ही यह तय करता है कि राजनीतिक और कानूनी संस्थाएं कैसी होंगी। अतः, यदि उत्पादन की पद्धति में परिवर्तन होता है, तो अनिवार्य रूप से अधिसंरचना में भी परिवर्तन आता है, जो वर्ग प्रभुत्व को दर्शाता है।

46. (B) लोकतंत्र केवल एक सत्तारूढ़ अभिजन को चुनने की एक प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया है।
लोकतंत्र का अभिजनवादी सिद्धांत इस पारंपरिक धारणा को चुनौती देता है कि जनता स्वयं शासन करती है। इसके बजाय, यह तर्क देता है कि आधुनिक लोकतंत्र वास्तव में एक ऐसी प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया है जिसमें मतदाता विभिन्न अभिजन समूहों या दलों में से चुनाव करते हैं जो उन पर शासन करेंगे। यहाँ लोकतंत्र का अर्थ नीतियों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण के स्थान पर नेताओं के बीच प्रतिस्पर्धा के माध्यम से सत्ता के हस्तांतरण की एक शांतिपूर्ण व्यवस्था है।

47. (D) गैब्रियल आलमंड और बिंघम पॉवेल
गैब्रियल आलमंड और बिंघम पॉवेल ने राजनीतिक विकास को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में देखा जिसमें राजनीतिक व्यवस्था अपनी समस्या-समाधान की क्षमता बढ़ाती है। उनके अनुसार, विकास का अर्थ व्यवस्था की कार्यक्षमता में वृद्धि, भूमिकाओं का विशिष्टीकरण और राजनीतिक संस्कृति का धर्मनिरपेक्षीकरण है। यह दृष्टिकोण केवल आर्थिक वृद्धि तक सीमित नहीं है, बल्कि यह इस बात पर केंद्रित है कि एक व्यवस्था नए दबावों और चुनौतियों का सामना करने के लिए खुद को कैसे अनुकूलित और विकसित करती है।

NODIA

48. (B) P-2, Q-1, R-4, S-3
राजनीतिक व्यवस्था के आगत कार्यों को उनके विशिष्ट विवरणों से सुमेलित किया जा सकता है। हित प्रकटीकरण मांगों को व्यक्त करने की प्रक्रिया है, जबकि हित समूहन उन मांगों को एक सुसंगत नीति कार्यक्रम में जोड़ने का कार्य है। राजनीतिक समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से राजनीतिक मूल्यों और मानदंडों को अगली पीढ़ी तक पहुँचाया जाता है। राजनीतिक संचार का अर्थ पूरे समाज में राजनीतिक रूप से प्रासंगिक जानकारी और संदेशों का प्रभावी प्रसार सुनिश्चित करना है, जो शासन के लिए आवश्यक है।

49. (C) राष्ट्रपति कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित होता है, जबकि संसदीय कार्यपालिका का कार्यकाल विधायिका के विश्वास पर निर्भर करता है।
राष्ट्रपति और संसदीय प्रणालियों के बीच सबसे मौलिक अंतर कार्यपालिका के कार्यकाल की स्थिरता और उसकी जवाबदेही के स्रोत में है। राष्ट्रपति प्रणाली में, राष्ट्रपति का कार्यकाल संवैधानिक रूप से निश्चित होता है और उसे सामान्यतः विधायी बहुमत द्वारा हटाया नहीं जा सकता। इसके विपरीत, संसदीय प्रणाली में, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल तब तक ही सत्ता में रह सकते हैं जब तक उन्हें विधायिका के निचले सदन का विश्वास प्राप्त होता है। यह संसदीय प्रणाली को अधिक उत्तरदायी लेकिन कभी-कभी कम स्थिर बनाता है।

50. (A) इसमें राज्यों के भीतर राजनीति और सरकार के सभी पहलू शामिल हैं।
तुलनात्मक राजनीति का दायरा अत्यंत व्यापक है, जिसमें केवल सरकारों की औपचारिक संरचनाओं का ही नहीं, बल्कि राज्यों के भीतर होने वाली सभी राजनीतिक गतिविधियों और व्यवहारों का अध्ययन शामिल है। इसमें राजनीतिक दल, दबाव समूह, जन आंदोलन, राजनीतिक संस्कृति और चुनावी प्रक्रियाओं का विश्लेषण किया जाता है। आधुनिक समय में, इसका विस्तार गैर-पश्चिमी समाजों और अनौपचारिक शक्ति संरचनाओं तक हो गया है, जिससे यह विभिन्न देशों की राजनीतिक वास्तविकताओं को समझने का एक समग्र और वैज्ञानिक अनुशासन बन गया है।

51. (C) केवल 1 और 2
डेविड ईस्टन का व्यवस्था दृष्टिकोण राजनीति को "समाज के लिए मूल्यों के आधिकारिक आवंटन" के रूप में परिभाषित करता है और राजनीतिक व्यवस्था को एक बाहरी पर्यावरण के भीतर सक्रिय मानता है। यह मॉडल आगत (मांगों और समर्थन) और निर्गत (निर्णयों) के बीच निरंतर अंतःक्रिया पर बल देता है। हालाँकि यह व्यवहार और प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करता है, लेकिन यह संस्थानों की भूमिका को पूरी तरह अनदेखा नहीं करता, बल्कि उन्हें उस रूपांतरण प्रक्रिया के हिस्से के रूप में देखता है जहाँ निर्णय लिए जाते हैं।

52. (B) तुलनात्मक राजनीति समिति, विशेष रूप से लुसियन पाई।
लुसियन पाई और तुलनात्मक राजनीति समिति ने यह प्रतिपादित किया कि राजनीतिक विकास की प्रक्रिया में राष्ट्रों को कई मूलभूत चुनौतियों या 'संकटों' का सामना करना पड़ता है। इनमें पहचान का संकट, वैधता का संकट, पैठ का संकट, भागीदारी का संकट और वितरण का संकट शामिल हैं। सफल राजनीतिक विकास इन संकटों के प्रभावी प्रबंधन और संस्थागत समाधान पर निर्भर करता है। यह ढांचा विशेष रूप से विकासशील देशों में राष्ट्र-निर्माण और राज्य-निर्माण की जटिलताओं को समझने के लिए एक व्यवस्थित विश्लेषण प्रदान करता है।

53. (C) 'शेर' और 'लोमड़ी'।
विल्फ्रेडो पेरेटो ने अपने अभिजन सिद्धांत में शासक वर्ग को उनके मनोवैज्ञानिक गुणों और शासन की शैलियों के आधार पर 'शेर' और 'लोमड़ी' में वर्गीकृत किया। 'शेर' वे अभिजन हैं जो बल प्रयोग, साहस और सीधेपन के माध्यम से शासन करते हैं, और वे अक्सर स्थिरता और परंपरा के पक्षधर होते हैं। इसके विपरीत, 'लोमड़ी' वे अभिजन हैं जो चतुराई, कूटनीति, हेरफेर और नवाचार के माध्यम से सत्ता बनाए रखते हैं। पेरेटो के अनुसार, इतिहास इन दो प्रकार के अभिजनों के संचलन की एक निरंतर प्रक्रिया है।

54. (D) राजनीतिक संचार
राजनीतिक संचार वह महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सूचनाओं और संदेशों का प्रवाह समाज, जनसंचार माध्यमों और राजनीतिक नेतृत्व के बीच होता है। जनसंचार माध्यम इस प्रक्रिया में 'द्वारपाल' के रूप में कार्य करते हैं, जो यह तय करते हैं कि कौन सी जानकारी जनता तक पहुँचेगी और किन मुद्दों को प्रमुखता दी जाएगी। यह नागरिकों की राजनीतिक धारणाओं, प्राथमिकताओं और निर्णयों को गहराई से प्रभावित करता है, जिससे यह लोकतंत्र में लोकमत के निर्माण का एक अनिवार्य आधार बन जाता है।

55. (A) न्यायाधीशों को सरकार की अन्य शाखाओं के राजनीतिक दबाव से मुक्त होना चाहिए।
न्यायिक स्वतंत्रता का सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि न्यायपालिका अपने निर्णयों को बिना किसी भय या पक्षपात के संवैधानिक आधार पर ले सके। इसका अर्थ है कि न्यायाधीशों पर कार्यपालिका या विधायिका का कोई अनुचित राजनीतिक दबाव नहीं होना चाहिए। इस स्वतंत्रता को सुरक्षित करने के लिए न्यायाधीशों का निश्चित कार्यकाल, सुरक्षित सेवा शर्तें और नियुक्ति की एक निष्पक्ष प्रक्रिया आवश्यक है। स्वतंत्र न्यायपालिका कानून के शासन को बनाए रखने और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए लोकतंत्र का एक अनिवार्य स्तंभ है।

56. (A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं और कथन II, कथन I की सही व्याख्या है।
संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण ने तुलनात्मक राजनीति में एक महत्वपूर्ण क्रांति की क्योंकि इसने विद्वानों को विविध राजनीतिक प्रणालियों की तुलना के लिए एक सार्वभौमिक ढांचा प्रदान किया। पारंपरिक दृष्टिकोण केवल पश्चिमी संस्थानों तक सीमित था, लेकिन इस नए दृष्टिकोण ने उन बुनियादी कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया जो सभी समाजों में किसी न किसी संरचना द्वारा किए जाते हैं। इसने विकासशील

Downloaded from www.pdf.tube

देशों की गैर-औपचारिक प्रणालियों को वैज्ञानिक विश्लेषण के दायरे में लाकर तुलनात्मक अध्ययन को अधिक व्यापक और व्यावहारिक बनाया।

57. (C) इसमें महत्वपूर्ण शक्तियों के साथ सीधे निर्वाचित राष्ट्रपति और संसद के प्रति उत्तरदायी प्रधानमंत्री दोनों होते हैं।
अर्ध-राष्ट्रपति प्रणाली, जिसे फ्रांस की शासन व्यवस्था के लिए जाना जाता है, राष्ट्रपति और संसदीय दोनों प्रणालियों के तत्वों का मिश्रण है। इसमें एक सीधे निर्वाचित राष्ट्रपति होता है जिसके पास व्यापक कार्यकारी शक्तियां होती हैं, और साथ ही एक प्रधानमंत्री होता है जो मंत्रिमंडल का नेतृत्व करता है और संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। यह व्यवस्था दोहरी कार्यपालिका की विशेषता रखती है, जहाँ शक्ति का संतुलन अक्सर राष्ट्रपति और विधायी बहुमत के बीच राजनीतिक संबंधों पर निर्भर करता है।

58. (A) सहभागी, प्रजाभावी और संकीर्ण संस्कृतियों का मिश्रण, जिसे लोकतंत्र के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है।
गैब्रियल आलमंड और सिडनी वर्बा ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'द सिविक कल्चर' में तर्क दिया कि एक स्थिर लोकतंत्र के लिए केवल सहभागी संस्कृति पर्याप्त नहीं है। इसके बजाय, एक ऐसी 'नागरिक संस्कृति' की आवश्यकता होती है जिसमें सहभागी सक्रियता, प्रजाभावी आज्ञाकारिता और संकीर्ण निष्ठाओं का एक संतुलित मिश्रण हो। यह संतुलन नागरिकों को सरकार को प्रभावित करने की शक्ति भी देता है और साथ ही शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक स्थिरता और कानूनी अनुपालन भी सुनिश्चित करता है।

59. (D) राजनीतिक अभिनेताओं, जैसे मतदाताओं और विधायकों का वास्तविक व्यवहार।
व्यवहारवादी दृष्टिकोण ने तुलनात्मक राजनीति के केंद्र को संवैधानिक दस्तावेजों और औपचारिक संस्थानों से हटाकर राजनीतिक अभिनेताओं के वास्तविक और दृश्य व्यवहार की ओर स्थानांतरित कर दिया। यह दृष्टिकोण मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्रीय विधियों का उपयोग करते हुए यह समझने का प्रयास करता है कि लोग मतदान क्यों करते हैं, विधायक निर्णय कैसे लेते हैं और राजनीतिक दल कैसे कार्य करते हैं। इसका उद्देश्य आनुभविक डेटा और वैज्ञानिक पद्धतियों के माध्यम से राजनीति के बारे में सामान्यीकरण और परीक्षण योग्य सिद्धांतों का निर्माण करना है।

60. (B) 2, 3, 4, 1
तुलनात्मक राजनीति के बौद्धिक इतिहास में सबसे पहले पारंपरिक, औपचारिक-कानूनी दृष्टिकोण का प्रभुत्व था। इसके बाद 1950 के दशक में डेविड ईस्टन द्वारा व्यवस्था दृष्टिकोण प्रतिपादित किया गया। 1956 में सी. राइट मिल्स ने 'द पावर एलीट' का प्रकाशन किया, जिसने शक्ति संरचनाओं के अध्ययन को नई दिशा दी। अंततः 1963 में आलमंड और वर्बा की 'द सिविक कल्चर' प्रकाशित हुई, जिसने राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा को वैश्विक मान्यता प्रदान की। यह क्रम इस विषय के विकास के विविध चरणों को स्पष्ट करता है।

61. (C) राज्य वर्गों के बीच एक तटस्थ मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है।
मार्क्सवादी दृष्टिकोण इस विचार को पूरी तरह नकारता है कि राज्य एक तटस्थ निकाय है। इसके विपरीत, यह मानता है कि राज्य समाज में प्रभावी आर्थिक वर्ग का एक साधन है जिसका उपयोग अन्य वर्गों के दमन और अपने प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए किया जाता है। मार्क्सवाद के अनुसार, राजनीति का मूल वर्ग संघर्ष है और राज्य की संरचना उत्पादन के आर्थिक आधार द्वारा निर्धारित होती है। पूंजीवाद के पतन के बाद ही वर्गविहीन समाज में राज्य की आवश्यकता समाप्त होगी।

62. (D) कार्यपालिका और नौकरशाही की तुलना में विधायिकाओं की शक्ति कम हो गई है।
'विधायिकाओं के पतन' का सिद्धांत यह इंगित करता है कि आधुनिक राज्यों में नीति निर्माण और शासन की वास्तविक शक्ति धीरे-धीरे निर्वाचित सदनों से कार्यपालिका और तकनीकी विशेषज्ञों (नौकरशाही) की ओर स्थानांतरित हो रही है। आधुनिक युग की जटिल समस्याओं और त्वरित निर्णय लेने की आवश्यकता ने कार्यपालिका के प्रभाव को बढ़ा दिया है। हालांकि विधायिकाएं अभी भी कानून बनाती हैं, लेकिन कानून के वास्तविक मसौदे तैयार करने और शासन के महत्वपूर्ण निर्णयों पर उनका प्रभावी नियंत्रण और निगरानी पहले की तुलना में कमजोर हुई है।

63. (A) इसके सजाति-केंद्रित होने और पश्चिम पर आधारित विकास के एकरेखीय पथ को मानने के कारण।
प्रारंभिक राजनीतिक आधुनिकीकरण सिद्धांतों की व्यापक आलोचना इसलिए की गई क्योंकि उन्होंने यह मान लिया था कि सभी देशों को पश्चिमी लोकतंत्र और औद्योगिकीकरण के एक ही रास्ते पर चलना होगा। इस दृष्टिकोण को 'सजाति-केंद्रित' माना गया क्योंकि इसने पश्चिमी मूल्यों को श्रेष्ठ और सार्वभौमिक माना। आलोचकों का तर्क था कि यह सिद्धांत गैर-पश्चिमी समाजों की अनूठी सांस्कृतिक विरासत, स्थानीय संदर्भों और विकास के वैकल्पिक मॉडलों की उपेक्षा करता है, जिससे विकासशील देशों की वास्तविक चुनौतियों को समझना कठिन हो जाता है।

64. (B) कानूनों को लागू करना और उनका पालन कराना।
सरकार की कार्यकारी शाखा का प्राथमिक और सबसे महत्वपूर्ण कार्य विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों और नीतियों को समाज में प्रभावी ढंग से लागू करना है। कार्यपालिका शासन का वह अंग है जो राज्य के प्रशासनिक तंत्र का संचालन करता है, कानून व्यवस्था बनाए रखता है और सार्वजनिक सेवाओं का प्रबंधन करता है। इसमें राष्ट्राध्यक्ष, सरकार का प्रमुख और संपूर्ण प्रशासनिक नौकरशाही शामिल होती है, जो मिलकर राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने और व्यवस्था की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होते हैं।

65. (A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।
लोकतंत्र का अभिजनवादी सिद्धांत यह प्रतिपादित करता है कि समाज के बड़े और जटिल होने के कारण एक छोटे संगठित अल्पसंख्यक का शासन अपरिहार्य हो जाता है, जिसे अभिजन

NODIA

कहा जाता है। इसके विपरीत, बहुलवादी सिद्धांत का तर्क है कि शक्ति किसी एक अभिजन समूह के पास नहीं होती, बल्कि यह विभिन्न प्रतिस्पर्धी समूहों के बीच व्यापक रूप से वितरित होती है। ये दोनों सिद्धांत आधुनिक लोकतंत्रों में शक्ति के वितरण और निर्णय लेने की प्रक्रिया को समझने के लिए विपरीत परंतु महत्वपूर्ण दृष्टिकोण प्रदान करते हैं।

66. (B) आपराधिक मामलों का अधिनिर्णयन
आधुनिक विधायिका का मुख्य कार्य कानून बनाना, सार्वजनिक वित्त (बजट) पर नियंत्रण रखना और कार्यकारी शाखा की गतिविधियों की निगरानी करना है। यह नागरिकों की इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला सर्वोच्च मंच होता है। आपराधिक मामलों का अधिनिर्णयन या न्याय प्रदान करना न्यायपालिका का एक विशिष्ट और स्वतंत्र कार्य है। शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के अनुसार, विधायिका को न्यायिक कार्यों में सीधे हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ताकि निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित हो सके और नागरिक अधिकारों की रक्षा की जा सके।

67. (D) राजनीतिक अभिवृत्तियों और व्यवहारों को सीखने और प्राप्त करने की आजीवन प्रक्रिया।
राजनीतिक समाजीकरण वह व्यापक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक राजनीति के प्रति अपने विश्वासों, मूल्यों और दृष्टिकोणों को विकसित करता है। यह प्रक्रिया केवल शिक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें परिवार, विद्यालय, कार्यस्थल और जनसंचार माध्यमों के माध्यम से मिलने वाले अनुभव भी शामिल हैं। यह व्यक्तियों को उनकी राजनीतिक व्यवस्था के भीतर एक सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार करती है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक राजनीतिक संस्कृति के हस्तांतरण को सुनिश्चित करती है।

68. (D) 1, 2 और 3
शास्त्रीय अभिजन सिद्धांतकारों ने शक्ति के केंद्रीकरण को समझाने के लिए महत्वपूर्ण विचार दिए हैं। विल्फ्रेडो पेरेटो ने अभिजनों को उनकी शासन शैली के आधार पर 'शेर' और 'लोमड़ी' के रूप में वर्गीकृत किया। गेटानो मोस्का ने यह तर्क दिया कि अल्पसंख्यक सत्तारूढ़ वर्ग अपनी बेहतर संगठनात्मक क्षमता के कारण बहुसंख्यक जनता पर शासन करता है। रॉबर्ट मिचल्स ने 'अल्पतंत्र का लौह नियम' प्रतिपादित करते हुए स्पष्ट किया कि बड़े संगठनों में सत्ता का केंद्रीकरण नेतृत्व के हाथों में होना एक अपरिहार्य प्रक्रिया है।

69. (C) वे संस्थाएं और प्रक्रियाएं जो आगत को निर्गत में बदलती हैं।
डेविड ईस्टन के राजनीतिक व्यवस्था मॉडल में 'रूपांतरण प्रक्रिया' वह केंद्रीय तंत्र है जहाँ जनता की मांगों और समर्थन (आगत) को आधिकारिक निर्णयों और नीतियों (निर्गत) में बदला जाता है। इसमें सरकार के विभिन्न अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका और नौकरशाही शामिल होते हैं। यह प्रक्रिया राजनीतिक व्यवस्था की वास्तविक कार्यप्रणाली को दर्शाती है, जहाँ विभिन्न दबावों को तौला जाता है और समाज के लिए मूल्यों का आवंटन किया जाता है। यह राजनीतिक व्यवस्था की जीवन-शक्ति और निर्णय लेने की क्षमता का केंद्र है।

70. (A) विश्लेषणात्मक और व्याख्यात्मक होने के बजाय वर्णनात्मक और औपचारिक होने की प्रवृत्ति।
तुलनात्मक राजनीति के पारंपरिक दृष्टिकोण की सबसे बड़ी कमजोरी इसकी वर्णनात्मक और कानूनी प्रकृति थी। यह दृष्टिकोण केवल विभिन्न देशों के संविधानों और सरकारी अंगों की औपचारिक संरचनाओं का विवरण देने तक सीमित था, लेकिन यह यह समझाने में विफल रहा कि वे संस्थान वास्तव में कैसे और क्यों कार्य करते हैं। इसमें राजनीतिक व्यवहार, अनौपचारिक प्रभाव और सामाजिक-आर्थिक कारकों की उपेक्षा की गई। इसके अतिरिक्त, इसका अत्यधिक पश्चिमी देशों पर केंद्रित होना इसे एक वैश्विक और वैज्ञानिक अनुशासन बनने से रोकता था।

71. (B) P-2, Q-1, R-3, S-4
तुलनात्मक राजनीति के प्रमुख विचारकों ने महत्वपूर्ण कृतियों के माध्यम से राजनीति विज्ञान को समृद्ध किया है। सैमुअल हंटिंगटन ने 'पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज' में संस्थाकरण और स्थिरता पर बल दिया। आलमंड और वर्बा ने 'द सिविक कल्चर' के माध्यम से राजनीतिक संस्कृति का विश्लेषण किया। सी. राइट मिल्स ने 'द पावर एलीट' में अमेरिका की शक्ति संरचना का चित्रण किया। जोसेफ शुम्पेटर ने 'कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी' में लोकतंत्र को अभिजनों के बीच एक प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया।

72. (B) न्यायपालिका
राजनीतिक विश्लेषण के संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक ढांचे में 'नियम अधिनिर्णयन' का कार्य मुख्य रूप से न्यायपालिका की भूमिका से मेल खाता है। इसका अर्थ है विशिष्ट मामलों में कानूनों की व्याख्या करना और यह निर्धारित करना कि किसी कानून का उल्लंघन हुआ है या नहीं। न्यायपालिका विवादों का निपटारा करती है और यह सुनिश्चित करती है कि शासन संविधान और कानून के सिद्धांतों के अनुसार चले। यह कार्य व्यवस्था की वैधता बनाए रखने और नागरिकों को न्याय प्रदान करने के लिए किसी भी लोकतांत्रिक प्रणाली में अनिवार्य माना जाता है।

73. (C) 'प्रासंगिकता' और 'कार्रवाई' पर जोर, शोध को सामाजिक समस्याओं से जोड़ना।
उत्तर-व्यवहारवादी आंदोलन 1960 के दशक के अंत में व्यवहारवाद की सीमाओं के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में उभरा। इसके समर्थकों ने तर्क दिया कि राजनीति विज्ञान को केवल मूल्य-मुक्त डेटा और तकनीकी शुद्धता पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे समाज की वास्तविक समस्याओं के प्रति 'प्रासंगिक' होना चाहिए। डेविड ईस्टन ने इसके दो मुख्य नारों—प्रासंगिकता और कार्रवाई—पर बल दिया। इसका उद्देश्य अकादमिक शोध को सामाजिक न्याय, शांति और परिवर्तन जैसे मानवीय मूल्यों से जोड़कर समाज के लिए अधिक उपयोगी बनाना था।

Click Here to Buy book on Amazon

74. (A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं और कथन II, कथन I की सही व्याख्या है।
संघीय शासन प्रणालियों में द्विसदनीय विधायिका का होना एक सामान्य और महत्वपूर्ण विशेषता है। इसका प्राथमिक कारण यह है कि जहाँ पहला सदन सीधे जनता का प्रतिनिधित्व करता है, वहीं दूसरा सदन (जैसे भारत में राज्यसभा या अमेरिका में सीनेट) संघ की घटक इकाइयों या राज्यों के हितों की रक्षा करता है। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाते समय क्षेत्रीय विविधता और राज्यों के अधिकारों का उचित सम्मान हो, जिससे केंद्र और राज्यों के बीच संतुलन बना रहता है।

75. (A) बुर्जुआ वर्ग की संपत्ति और हितों की रक्षा करना।
मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार, पूंजीवादी समाज में राज्य का प्राथमिक उद्देश्य समाज के प्रभावी आर्थिक वर्ग, जिसे बुर्जुआ कहा जाता है, के हितों का संरक्षण करना है। राज्य एक दमनकारी यंत्र के रूप में कार्य करता है जो निजी संपत्ति की रक्षा करता है और सर्वहारा वर्ग के शोषण को वैध बनाता है। राजनीति और कानून को आर्थिक आधार की अधिसंरचना माना जाता है, जिसका अर्थ है कि राज्य कभी भी तटस्थ नहीं हो सकता, बल्कि वह हमेशा सत्तारुढ़ वर्ग के प्रभुत्व को बनाए रखता है।

76. (B) हेरोल्ड लासवेल
"कौन क्या, कब और कैसे प्राप्त करता है" राजनीति की यह अत्यंत प्रभावशाली परिभाषा हेरोल्ड लासवेल द्वारा दी गई थी। यह परिभाषा राजनीति के केंद्र में 'शक्ति' और 'संसाधनों के वितरण' को रखती है। लासवेल का मानना था कि राजनीति का अध्ययन मुख्य रूप से समाज में प्रभाव और मूल्यों के आवंटन का अध्ययन है। यह दृष्टिकोण केवल औपचारिक संस्थानों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उन प्रक्रियाओं की जांच करता है जिनके माध्यम से विभिन्न समूह और व्यक्ति अपने हितों को सिद्ध करने के लिए शक्ति का प्रयोग करते हैं।

77. (B) पैठ का संकट
लुसियन पाई द्वारा वर्णित 'पैठ का संकट' उस स्थिति को संदर्भित करता है जहाँ एक नई या विकासशील केंद्र सरकार पूरे राष्ट्र की सीमाओं के भीतर अपने प्रभावी प्रशासनिक और राजनीतिक नियंत्रण को स्थापित करने में कठिनाई महसूस करती है। यह संकट तब उत्पन्न होता है जब सरकारी नीतियों और कानूनों का पालन ग्रामीण या दूरस्थ क्षेत्रों में नहीं हो पाता है। इसे हल करने के लिए राज्य को एक मजबूत नौकरशाही और संचार तंत्र की आवश्यकता होती है जो केंद्र और स्थानीय समाज के बीच एक सेतु का निर्माण कर सके।

78. (A) नियंत्रण और संतुलन के साथ शक्ति पृथक्करण की प्रणाली।
संयुक्त राज्य अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था मोंटेस्क्यू के 'शक्तियों के पृथक्करण' के सिद्धांत पर आधारित है। यहाँ विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को संवैधानिक रूप से एक-दूसरे से स्वतंत्र रखा गया है। इस स्वतंत्रता के साथ 'नियंत्रण और संतुलन' की एक जटिल व्यवस्था भी लागू है, जो यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी एक अंग अत्यधिक शक्तिशाली न हो जाए। उदाहरण के लिए, राष्ट्रपति के पास वीटो शक्ति है, जबकि संसद के पास राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने और न्यायपालिका के पास कानूनों की समीक्षा करने का अधिकार है।

79. (C) राजनीतिक समाजीकरण
राजनीतिक समाजीकरण वह निरंतर सामाजिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी समाज की राजनीतिक संस्कृति, जिसमें मूल्य, विश्वास और मानदंड शामिल हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित की जाती है। इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य समाज में राजनीतिक स्थिरता और निरंतरता बनाए रखना है। परिवार, विद्यालय, संस्थाएं और जनसंचार माध्यम इस कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह प्रक्रिया न केवल व्यक्तियों को उनकी राजनीतिक पहचान प्रदान करती है, बल्कि उन्हें व्यवस्था के भीतर सक्रिय नागरिक बनने के लिए आवश्यक कौशलों से भी लैस करती है।

80. (B) जर्मन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी
रॉबर्ट मिचल्स ने अपना प्रसिद्ध 'अल्पतंत्र का लौह नियम' जर्मन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के गहन अध्ययन के आधार पर विकसित किया था। उन्होंने यह देखकर आश्चर्य व्यक्त किया कि एक पार्टी जो समाज में लोकतंत्र और समानता के लिए संघर्ष कर रही थी, वह स्वयं अपने आंतरिक कामकाज में अत्यधिक अल्पतांत्रिक और केंद्रीकृत थी। इस निष्कर्ष ने उन्हें यह प्रतिपादित करने के लिए प्रेरित किया कि संगठनात्मक जटिलता अनिवार्य रूप से नेतृत्व के हाथों में शक्ति का केंद्रीकरण करती है, चाहे उस संगठन की विचारधारा कितनी भी लोकतांत्रिक क्यों न हो।

81. (D) जन समर्थन
डेविड ईस्टन के सामान्य व्यवस्था मॉडल में जन समर्थन को 'आगत' के रूप में वर्गीकृत किया गया है, न कि निर्गत के रूप में। आगत में जनता की मांगें और व्यवस्था के प्रति उनका समर्थन शामिल होता है जो पर्यावरण से आता है। इसके विपरीत, 'निर्गत' उन आधिकारिक निर्णयों, कानूनों और नीतियों को कहा जाता है जो राजनीतिक व्यवस्था रूपांतरण प्रक्रिया के बाद समाज को प्रदान करती है। जन समर्थन वह आधार है जो व्यवस्था को क्रियान्वित रखता है, जबकि निर्गत उसके द्वारा किए गए ठोस कार्यों का परिणाम होते हैं।

82. (A) राजनीतिक प्रणालियाँ खुद को कैसे बनाए रखती हैं और अनुकूलित करती हैं।
संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण का मुख्य लक्ष्य यह विश्लेषण करना है कि राजनीतिक प्रणालियाँ अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए किन आवश्यक कार्यों को पूरा करती हैं और वे बदलते परिवेश के प्रति खुद को कैसे अनुकूलित करती हैं। यह दृष्टिकोण उन विशिष्ट संरचनाओं की भूमिका की जांच करता है जो व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अनिवार्य प्रकार्यों को निष्पादित करती हैं। इसका उद्देश्य विविध समाजों के बीच तुलना का एक ऐसा ढांचा प्रदान करना है जो केवल

NODIA

औपचारिक कानूनों के बजाय वास्तविक राजनीतिक प्रक्रियाओं पर आधारित हो।

83. (A) केवल 1 और 2
संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका के सदस्य अनिवार्य रूप से विधायिका के भी सदस्य होते हैं, जो शक्तियों के संलयन को दर्शाता है। इसके विपरीत, राष्ट्रपति प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका से स्वतंत्र होती है और उसका कार्यकाल विधायी विश्वास पर निर्भर नहीं होता है। हालाँकि, यह कहना अनुचित है कि राष्ट्राध्यक्ष और सरकार के प्रमुख हमेशा एक ही व्यक्ति होते हैं; संसदीय प्रणाली में ये दोनों पद अलग-अलग व्यक्तियों के पास होते हैं, जबकि राष्ट्रपति प्रणाली में ये एक ही व्यक्ति के पास होते हैं।

84. (D) राजनीतिक शक्ति एक छोटे अल्पसंख्यक के पास होती है।
'राजनीतिक अभिजन' की अवधारणा इस मूल विचार पर आधारित है कि प्रत्येक समाज में, चाहे वह लोकतांत्रिक हो या सत्तावादी, वास्तविक शक्ति हमेशा एक छोटे और संगठित अल्पसंख्यक समूह के हाथों में केंद्रित रहती है। ये अभिजन अपनी संपत्ति, शिक्षा, सामाजिक स्थिति या संगठनात्मक कौशल के कारण सामान्य जनता से भिन्न होते हैं। यह सिद्धांत इस धारणा को चुनौती देता है कि लोकतंत्र में शक्ति वास्तव में जनता के पास होती है, और यह तर्क देता है कि राजनीति अंततः अभिजनों के बीच सत्ता के लिए एक संघर्ष है।

85. (C) कारण: साक्षरता और संचार माध्यमों के प्रसार का उच्च स्तर। प्रभाव: राजनीतिक भागीदारी में वृद्धि।
राजनीतिक आधुनिकीकरण सिद्धांत के अनुसार, शिक्षा, साक्षरता और संचार माध्यमों का विस्तार नागरिकों की जागरूकता और आकांक्षाओं को बढ़ाता है। जैसे-जैसे लोग अधिक शिक्षित और सूचना संपन्न होते हैं, वे राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने की अधिक मांग करते हैं, जिससे राजनीतिक भागीदारी में वृद्धि होती है। यह सामाजिक-आर्थिक विकास और राजनीतिक परिवर्तन के बीच एक सीधा कार्यात्मक संबंध स्थापित करता है। हालाँकि, यदि राजनीतिक संस्थाएं इस बढ़ती भागीदारी को व्यवस्थित करने में सक्षम नहीं होती हैं, तो इससे व्यवस्था में अस्थिरता भी उत्पन्न हो सकती है।

86. (B) "द सिविक कल्चर"
तुलनात्मक राजनीति में 'राजनीतिक संस्कृति' की अवधारणा को गैब्रियल आलमंड और सिडनी वर्बा द्वारा 1963 में प्रकाशित उनकी युगांतरकारी पुस्तक "द सिविक कल्चर" के बाद व्यापक प्रमुखता मिली। इस अध्ययन ने पाँच देशों के नागरिकों की मनोवैज्ञानिक अभिवृत्तियों और उनके लोकतंत्र की स्थिरता के बीच संबंधों की जांच की। इस कार्य ने यह सिद्ध किया कि किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था की सफलता केवल उसके संविधान पर नहीं, बल्कि उसके नागरिकों के मूल्यों और विश्वासों के स्वरूप पर निर्भर करती है।

87. (D) एक आदर्शात्मक और कानूनी-संस्थागत केंद्र बिंदु।
तुलनात्मक राजनीति का पारंपरिक दृष्टिकोण मुख्य रूप से आदर्शात्मक और कानूनी-संस्थागत विशेषताओं द्वारा परिभाषित होता है। इसमें विद्वानों का ध्यान सरकारी अंगों की औपचारिक संरचनाओं, संवैधानिक प्रावधानों और संप्रभुता के कानूनी पहलुओं के वर्णन पर केंद्रित रहता था। यह दृष्टिकोण राजनीति के वास्तविक व्यवहार और अनौपचारिक प्रक्रियाओं के बजाय इस पर अधिक जोर देता था कि संस्थानों को आदर्श रूप में कैसा होना चाहिए। इसका विश्लेषण अक्सर केवल पश्चिमी देशों की सरकारों के अध्ययन तक ही सीमित रहता था, जिससे इसका दायरा काफी संकुचित था।

88. (A) आगत: 1, 3; निर्गत: 2, 4
डेविड ईस्टन और गैब्रियल आलमंड के मॉडलों के अनुसार, राजनीतिक व्यवस्था के कार्यों को आगत और निर्गत में विभाजित किया जा सकता है। आगत कार्यों में हित प्रकटीकरण और राजनीतिक समाजीकरण शामिल हैं, क्योंकि ये समाज से व्यवस्था की ओर मांगें और समर्थन लाते हैं। इसके विपरीत, नियम निर्माण और नियम अधिनिर्णयन निर्गत कार्यों की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि ये व्यवस्था द्वारा लिए गए आधिकारिक निर्णय और कार्य हैं जो समाज को प्रभावित करते हैं। यह विभाजन राजनीतिक प्रक्रिया के प्रवाह को समझने में मदद करता है।

89. (C) राजनीतिक व्यवस्था अंतःक्रियाओं का एक समूह है जो अपने पर्यावरण से अलग पहचाने जाने योग्य है।
राजनीति के व्यवस्था दृष्टिकोण की एक प्रमुख मान्यता यह है कि राजनीतिक व्यवस्था समाज के अन्य हिस्सों से अलग एक स्वायत्त इकाई के रूप में पहचानी जा सकती है, फिर भी वह अपने बाहरी पर्यावरण के साथ निरंतर अंतःक्रिया करती है। यह पर्यावरण से आगत प्राप्त करती है और उसे निर्गत में बदलकर वापस पर्यावरण में भेजती है। यह दृष्टिकोण राजनीति को एक गतिशील प्रक्रिया के रूप में देखता है जहाँ व्यवस्था का मुख्य लक्ष्य बदलते दबावों के बीच संतुलन बनाए रखना और अपना अस्तित्व सुरक्षित करना होता है।

90. (A) संयुक्त राज्य अमेरिका
तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य में, 'न्यायिक समीक्षा' की शक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे प्रभावी और मजबूत मानी जाती है। वहाँ का उच्चतम न्यायालय संविधान का अंतिम व्याख्याकार है और उसके पास विधायिका द्वारा पारित कानूनों तथा राष्ट्रपति के कार्यकारी कार्यों को असंवैधानिक घोषित करने का व्यापक अधिकार है। यह शक्ति 1803 के 'मार्बरी बनाम मैडिसन' मामले से स्थापित हुई थी। इसके विपरीत, यूनाइटेड किंगडम जैसी संसदीय संप्रभुता वाली प्रणालियों में न्यायालयों की शक्तियां अपेक्षाकृत सीमित होती हैं, जो अमेरिकी मॉडल को न्यायिक सर्वोच्चता का एक विशिष्ट उदाहरण बनाती हैं।

91. (A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।
सैमुअल हंटिंगटन के अनुसार, आधुनिकीकरण की तीव्र प्रक्रिया अक्सर सामाजिक और आर्थिक बदलाव लाती है जो लोगों की राजनीतिक भागीदारी की आकांक्षाओं को बढ़ा देती है। यदि किसी देश की राजनीतिक संस्थाएं (जैसे दल और कानूनी ढांचा) इन बढ़ती मांगों को आत्मसात करने के लिए पर्याप्त रूप से विकसित नहीं होती हैं, तो एक 'संस्थागत अंतराल' पैदा हो जाता है। यह अंतराल समाज में तनाव, हिंसा और अस्थिरता

Downloaded from www.pdf.tube

उत्पन्न करता है, जिसे हंटिंगटन ने 'राजनीतिक पतन' कहा है। अतः, स्थिरता के लिए संस्थाकरण की गति का आधुनिकीकरण के अनुरूप होना आवश्यक है।

92. (B) राजनीतिक संचार
राजनीतिक संचार वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सूचनाएं, विचारधाराएं और संदेश राजनीतिक व्यवस्था और समाज के बीच प्रवाहित होते हैं। इसमें संचार माध्यम, प्रेस और डिजिटल प्लेटफॉर्म महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो सरकारी निर्णयों को जनता तक पहुँचाते हैं और जनमत को सरकार तक पहुँचाते हैं। यह केवल सूचना का प्रेषण नहीं है, बल्कि यह राजनीतिक धारणाओं के निर्माण और नागरिकों के व्यवहार को प्रभावित करने का एक शक्तिशाली उपकरण है, जो किसी भी आधुनिक लोकतंत्र की कार्यप्रणाली के लिए आधारभूत माना जाता है।

93. (C) सी. राइट मिल्स
जोसेफ शुम्पेटर द्वारा प्रस्तुत किया गया यह विचार कि लोकतंत्र प्रतिस्पर्धा के माध्यम से नेताओं को चुनने की एक प्रक्रियात्मक व्यवस्था है, उनके प्रतिस्पर्धी अभिजनवाद के सिद्धांत का हिस्सा है। शुम्पेटर का तर्क था कि लोकतंत्र का अर्थ 'जनता द्वारा शासन' नहीं है, बल्कि यह नेताओं के बीच जनता के मतों के लिए एक प्रतिस्पर्धा है। यहाँ नागरिकों की भूमिका केवल अपने शासकों का चयन करने तक सीमित है, न कि नीति निर्माण में सीधे भाग लेने की। यह दृष्टिकोण लोकतंत्र को एक यथार्थवादी और प्रक्रियात्मक रूप में परिभाषित करता है।

94. (D) न्यायिक नियुक्तियों की प्रक्रिया।
कार्यपालिकाओं के तुलनात्मक अध्ययन में मुख्य रूप से राष्ट्राध्यक्ष और सरकार के प्रमुख के बीच संबंध, कार्यपालिका की विधायी शक्तियों और मंत्रिमंडल की विधायिका के प्रति जवाबदेही का विश्लेषण किया जाता है। न्यायिक नियुक्तियों की प्रक्रिया, हालांकि महत्वपूर्ण है, लेकिन यह मुख्य रूप से न्यायपालिका के ढांचे और उसकी स्वतंत्रता से संबंधित विषय है। कार्यकारी अध्ययन का केंद्र इस बात पर होता है कि शासन की सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग कैसे किया जाता है और वह अन्य विधायी अंगों के साथ किस प्रकार अंतःक्रिया करती है।

95. (A) आदर्शात्मक निर्धारण से आनुभविक व्याख्या की ओर बदलाव।
तुलनात्मक राजनीति में पारंपरिक से आधुनिक चरण में संक्रमण की मुख्य विशेषता यह है कि अब विद्वान केवल यह नहीं बताते कि सरकार को कैसा होना चाहिए, बल्कि वे यह विश्लेषण करते हैं कि राजनीति वास्तव में कैसे कार्य करती है। इस बदलाव ने शोध में वैज्ञानिक पद्धतियों, डेटा संग्रह और सिद्धांत निर्माण को प्राथमिकता दी। अब ध्यान केवल कानूनी संस्थानों के विवरण पर नहीं, बल्कि राजनीतिक व्यवहार, प्रक्रियाओं और उन कारकों पर केंद्रित है जो विभिन्न प्रणालियों के प्रदर्शन को प्रभावित करते हैं।

96. (B) P-2, Q-3, R-4, S-1
व्यवस्था सिद्धांत के तकनीकी शब्दों का अपना विशिष्ट महत्व है। 'आगत' पर्यावरण से प्राप्त मांगों और समर्थन को संदर्भित करता है, जबकि 'निर्गत' व्यवस्था द्वारा लिए गए आधिकारिक निर्णयों और नीतियों को दर्शाता है। 'प्रतिपुष्टि तंत्र' वह सूचना मार्ग है जो निर्गत के प्रभाव को वापस आगत के रूप में व्यवस्था तक पहुँचाता है। 'पर्यावरण' उन सभी बाहरी सामाजिक, आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों को कहते हैं जिनमें राजनीतिक व्यवस्था कार्य करती है। यह संरचना व्यवस्था की गतिशीलता और निरंतरता को समझने में सहायक है।

97. (C) सैमुअल हंटिंगटन
'राजनीतिक पतन' की अवधारणा सैमुअल हंटिंगटन द्वारा उनकी प्रसिद्ध कृति 'पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज' में प्रस्तुत की गई थी। उन्होंने तर्क दिया कि तीव्र सामाजिक परिवर्तन और बढ़ती राजनीतिक भागीदारी, यदि मजबूत राजनीतिक संस्थानों के विकास के बिना होती है, तो वह व्यवस्था की स्थिरता को नष्ट कर देती है। हंटिंगटन का मानना था कि आधुनिकीकरण हमेशा प्रगति नहीं लाता; कभी-कभी यह अव्यवस्था और संस्थागत विफलता का कारण बनता है। यह विचार विकासशील देशों में राजनीतिक स्थिरता और व्यवस्था के महत्व को रेखांकित करता है।

98. (A) अल्पसंख्यक द्वारा शासन सामाजिक जीवन की एक अपरिहार्य विशेषता है।
शास्त्रीय अभिजन सिद्धांतकारों, जैसे मोस्का, पेरेटो और मिचल्स का मूल तर्क यह है कि प्रत्येक समाज में, उसकी शासन प्रणाली चाहे जो भी हो, शक्ति हमेशा एक छोटे संगठित अल्पसंख्यक के हाथों में रहती है। वे मानते हैं कि बहुसंख्यक जनता हमेशा असंगठित और नेतृत्व की मोहताज होती है, जबकि अभिजन अपनी विशिष्ट क्षमताओं और संगठन के कारण शासन करने में सक्षम होते हैं। उनके अनुसार, लोकतंत्र भी वास्तव में अभिजनों के बीच सत्ता के लिए एक प्रतिस्पर्धा मात्र है, जिसमें जनभागीदारी केवल नाममात्र की होती है।

99. (C) वह सिद्धांत कि सरकार की प्रत्येक शाखा दूसरों को सीमित कर सकती है।
तुलनात्मक सरकार में 'नियंत्रण और संतुलन' का सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि सरकार की तीनों शाखाएं—विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका—अपनी संवैधानिक सीमाओं के भीतर रहकर कार्य करें। इस व्यवस्था में प्रत्येक अंग के पास दूसरे अंगों की शक्तियों पर अंकुश लगाने के कुछ अधिकार होते हैं। उदाहरण के लिए, न्यायपालिका कानूनों की समीक्षा कर सकती है, जबकि विधायिका कार्यपालिका पर नियंत्रण रख सकती है। यह तंत्र शक्ति के दुरुपयोग को रोकने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए किसी भी लोकतांत्रिक शासन में अपरिहार्य माना जाता है।

100. (A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं और कथन II, कथन I की सही व्याख्या है।
परिवार को राजनीतिक समाजीकरण का सबसे प्रभावशाली और प्राथमिक अभिकर्ता माना जाता है क्योंकि बच्चा अपने जीवन के शुरुआती और सबसे ग्रहणशील वर्षों में परिवार के संपर्क में रहता है। माता-पिता के राजनीतिक झुकाव, चर्चाएं और दृष्टिकोण अनजाने में बच्चे के मन में घर कर जाते हैं, जो

NODIA

उसके भविष्य के राजनीतिक विश्वासों की आधारशिला बनते हैं। यह प्रारंभिक प्रभाव अक्सर इतना गहरा होता है कि व्यक्ति बड़े होने पर भी उन्हीं आधारभूत मूल्यों और पहचानों के प्रति वफादार बना रहता है जो उसने बचपन में अपने परिवार से सीखी थीं।

101. (C) उत्पादन के संबंध और शक्तियां।
मार्क्सवादी विश्लेषण में समाज का 'आधार' आर्थिक ढांचे से निर्मित होता है, जिसमें उत्पादन की शक्तियाँ और उत्पादन के संबंध शामिल होते हैं। यही आधार समाज की राजनीतिक और कानूनी 'अधिसंरचना' को आकार देता है। कार्ल मार्क्स का तर्क था कि जो वर्ग उत्पादन के साधनों को नियंत्रित करता है, वही राज्य और विचारधारा पर भी नियंत्रण रखता है। अतः, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन केवल तभी संभव है जब आर्थिक आधार में बदलाव आए, जो वर्ग संघर्ष के माध्यम से उत्पादक शक्तियों के विकास का परिणाम होता है।

102. (B) अभिजनवादी
गैब्रियल आलमंड और सिडनी वर्बा द्वारा विकसित 'नागरिक संस्कृति' के ढांचे में मुख्य रूप से तीन प्रकार की राजनीतिक संस्कृतियाँ पहचानी गई हैं: संकीर्ण, प्रजाभावी और सहभागी। 'अभिजनवादी' इस वर्गीकरण का हिस्सा नहीं है, क्योंकि यह नागरिकों के व्यवहार के बजाय शासन करने वाले वर्ग के सिद्धांत को दर्शाता है। एक सफल नागरिक संस्कृति इन तीनों का संतुलित मिश्रण होती है, जो व्यवस्था को स्थिरता और प्रभावशीलता प्रदान करती है। यह ढांचा लोकतंत्र की सफलता के मनोवैज्ञानिक आधारों को समझने में मदद करता है।

103. (D) इसमें व्यवस्था के अनुरक्षण के प्रति एक रूढ़िवादी झुकाव है।
संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण की सबसे प्रमुख आलोचना यह है कि यह राजनीतिक व्यवस्था की स्थिरता और अस्तित्व बनाए रखने पर अत्यधिक बल देता है। आलोचकों का तर्क है कि यह दृष्टिकोण यथास्थिति का समर्थन करता है और सामाजिक परिवर्तन, संघर्ष या क्रांतिकारी बदलावों को पर्याप्त रूप से स्पष्ट करने में विफल रहता है। इसका 'रूढ़िवादी झुकाव' इसे उन प्रणालियों का विश्लेषण करने के लिए कम प्रभावी बनाता है जहाँ तीव्र राजनीतिक उथल-पुथल हो रही हो, क्योंकि यह व्यवस्था के संतुलन को ही इसका आदर्श लक्ष्य मान लेता है।

104. (A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।
सरकार के अंगों के कार्यों का पारंपरिक विभाजन यह स्पष्ट करता है कि विधायिका का मुख्य उत्तरदायित्व समाज के लिए सामान्य नियमों और कानूनों का निर्माण करना है। इसके साथ ही, कार्यपालिका का प्राथमिक कार्य विधायिका द्वारा निर्मित उन नियमों और नीतियों को वास्तविक धरातल पर लागू करना और प्रशासनिक तंत्र का संचालन करना है। ये दोनों कथन शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के कार्यात्मक आधार को दर्शाते हैं, जो यह सुनिश्चित करता है कि कानून निर्माण और उसका क्रियान्वयन अलग-अलग अंगों द्वारा संतुलित रूप से किया जाए।

105. (C) राजनीतिक आधुनिकीकरण
राजनीतिक आधुनिकीकरण वह बहुआयामी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक पारंपरिक समाज धीरे-धीरे आधुनिक राजनीतिक विशेषताओं को अपनाता है। इसमें प्राधिकार का युक्तिकरण, राजनीतिक भूमिकाओं का विशिष्टीकरण और नागरिकों की राजनीतिक भागीदारी में व्यापक वृद्धि शामिल है। यह प्रक्रिया अक्सर औद्योगिकीकरण, शहरीकरण और शिक्षा के प्रसार के साथ जुड़ी होती है। इसका मुख्य लक्ष्य राजनीतिक व्यवस्था की क्षमता को बढ़ाना है ताकि वह आधुनिक जीवन की जटिल मांगों और तनावों का प्रभावी ढंग से सामना कर सके और समाज में स्थिरता बनी रहे।

106. (A) मूल्य-मुक्त और आनुभविक होने का प्रयास करता है।
व्यवहारवादी दृष्टिकोण ने तुलनात्मक राजनीति में एक क्रांतिकारी बदलाव लाया क्योंकि इसने शोध को व्यक्तिगत प्राथमिकताओं या आदर्शात्मक प्रश्नों से दूर रखा। इसका मुख्य लक्ष्य 'क्या है' का अध्ययन करना और वस्तुनिष्ठ डेटा के आधार पर तथ्यों को समझना था। यह दृष्टिकोण वैज्ञानिक पद्धतियों, सांख्यिकीय विश्लेषण और अवलोकन योग्य व्यवहार पर जोर देता है ताकि राजनीतिक सिद्धांतों को अधिक सटीक और सत्यापन योग्य बनाया जा सके। यह पारंपरिक दृष्टिकोण की कानूनी और दार्शनिक सीमाओं को चुनौती देकर राजनीति विज्ञान को एक आधुनिक विज्ञान के रूप में स्थापित करता है।

107. (D) ब्रिटिश संसदीय प्रणाली
'छाया मंत्रिमंडल' ब्रिटिश संसदीय प्रणाली की एक अनूठी और विशिष्ट विशेषता है। इसमें मुख्य विपक्षी दल अपने वरिष्ठ सदस्यों की एक ऐसी टीम बनाता है जो सत्तारूढ़ मंत्रिमंडल के प्रत्येक मंत्री के कार्यों की निगरानी करती है और वैकल्पिक नीतियां प्रस्तुत करती है। इसका मुख्य उद्देश्य सरकार को जवाबदेह बनाना और जनता को यह दिखाना है कि विपक्ष सत्ता संभालने के लिए सदैव तैयार है। यह व्यवस्था संसदीय लोकतंत्र में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और शासन की निरंतरता सुनिश्चित करने का एक प्रभावी उपकरण मानी जाती है।

108. (B) विल्फ्रेडो पेरेटो
'अभिजनों का संचलन' की अवधारणा विल्फ्रेडो पेरेटो द्वारा विस्तार से समझाई गई थी। उनका तर्क था कि समाज में शक्ति कभी भी स्थाई नहीं होती; बल्कि एक अभिजन समूह समय के साथ अपनी ऊर्जा खो देता है और उसका स्थान एक नया, अधिक सक्षम समूह ले लेता है। पेरेटो ने इस प्रक्रिया को 'इतिहास अभिजनों का कब्रिस्तान है' कहकर स्पष्ट किया। उन्होंने शासक वर्ग के भीतर मनोवैज्ञानिक बदलावों और शक्ति के हस्तांतरण की शैलियों का विश्लेषण किया, जो उनके समाजशास्त्रीय सिद्धांत का एक केंद्रीय स्तंभ है।

109. (C) पारंपरिक निष्ठाओं का सुदृढ़ीकरण
राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में पारंपरिक निष्ठाओं, जैसे कबीलावाद या संकीर्ण धार्मिक पहचानों का सुदृढ़ीकरण नहीं होता, बल्कि उनका स्थान व्यापक राष्ट्रीय पहचान और तर्कसंगत-कानूनी निष्ठाएं ले लेती हैं। आधुनिकीकरण में प्राधिकार का युक्तिकरण, भूमिकाओं का विशिष्टीकरण और

Click Here to Buy book on Amazon

जनभागीदारी में वृद्धि शामिल होती है। इसका उद्देश्य समाज को एक अधिक एकीकृत और कार्यात्मक रूप में बदलना है जहाँ व्यक्ति अपनी संकीर्ण पहचानों से ऊपर उठकर राष्ट्र-राज्य की राजनीतिक व्यवस्था के प्रति जागरूक और सहभागी बनते हैं।

110. (A) 2, 3, 1, 4
लुसियन पाई ने राजनीतिक विकास की प्रक्रिया में आने वाले संकटों को एक तार्किक क्रम में व्यवस्थित किया है। सबसे पहले एक राष्ट्र के रूप में 'पहचान' का संकट आता है, जिसके बाद शासन के अधिकार को स्वीकार कराने हेतु 'वैधता' का संकट उत्पन्न होता है। इसके उपरांत, नागरिकों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल करने के लिए 'भागीदारी' का संकट और अंततः संसाधनों के उचित वितरण हेतु 'वितरण' का संकट सामने आता है। इन संकटों का सफल समाधान ही किसी राजनीतिक व्यवस्था के परिपक्व विकास और स्थिरता को सुनिश्चित करता है।

111. (D) मार्क्सवादी दृष्टिकोण
मार्क्सवादी दृष्टिकोण राजनीति को वर्ग संघर्ष के माध्यम से देखता है और तर्क देता है कि राज्य कोई तटस्थ संस्था नहीं है, बल्कि यह आर्थिक रूप से शक्तिशाली वर्ग के हाथों में शोषण का एक यंत्र है। इस दृष्टिकोण के अनुसार, समाज का आर्थिक ढांचा ही उसकी राजनीतिक और कानूनी व्यवस्था को निर्धारित करता है। राजनीति का मुख्य उद्देश्य बुर्जुआ वर्ग के हितों की रक्षा करना और सर्वहारा वर्ग के विद्रोह को दबाना है। अतः, राजनीतिक विश्लेषण के केंद्र में आर्थिक उत्पादन के संबंध और वर्ग हित होते हैं।

112. (B) न्यायिक समीक्षा
न्यायिक समीक्षा वह संवैधानिक शक्ति है जिसके माध्यम से न्यायालय विधायिका द्वारा पारित कानूनों और कार्यपालिका के निर्णयों की वैधता की जाँच करते हैं। यदि कोई कानून संविधान की मूल भावना या प्रावधानों के विरुद्ध पाया जाता है, तो न्यायपालिका उसे रद्द या असंवैधानिक घोषित कर सकती है। यह शक्ति संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखने और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए अनिवार्य है। यह शक्तियों के पृथक्करण के ढांचे में एक प्रभावी नियंत्रण और संतुलन का कार्य करती है, जिससे शासन मर्यादित रहता है।

113. (D) 1, 2 और 3
तुलनात्मक पद्धति राजनीति विज्ञान का एक अनिवार्य उपकरण है जिसका उद्देश्य विभिन्न राजनीतिक प्रणालियों के बीच समानताओं और विविधताओं की पहचान करना है। यह पद्धति केवल विवरण तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका मुख्य लक्ष्य राजनीतिक व्यवहार और संस्थानों के बारे में सामान्यीकरण विकसित करना और प्राप्त डेटा का वैज्ञानिक परीक्षण करना है। समय के साथ यह अनुशासन केवल औपचारिक संस्थाओं के वर्णन से हटकर जटिल प्रक्रियाओं के सूक्ष्म विश्लेषण की ओर विकसित हुआ है, जिससे यह आधुनिक राजनीति को समझने के लिए अधिक विश्लेषणात्मक और सटीक बन गया है।

114. (A) समाज के माध्यम से राजनीतिक रूप से प्रासंगिक जानकारी का प्रवाह।
'राजनीतिक संचार' शब्द का प्रयोग उन सूचनाओं, संदेशों और प्रतीकों के आदान-प्रदान के लिए किया जाता है जो समाज में राजनीतिक प्रक्रियाओं और जनमत को प्रभावित करते हैं। इसमें सरकार से जनता की ओर जाने वाली सूचनाएं और जनता की ओर से सरकार तक पहुँचने वाली प्रतिक्रियाएं दोनों शामिल हैं। जनसंचार माध्यम, राजनीतिक दल और डिजिटल प्लेटफॉर्म इस संचार के मुख्य वाहक हैं। यह प्रक्रिया किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में पारदर्शिता, जागरूकता और नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

115. (C) राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य
सी. राइट मिल्स ने अपनी पुस्तक 'द पावर एलीट' में यह तर्क दिया कि संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे आधुनिक औद्योगिक समाज में वास्तविक शक्ति एक छोटे, एकीकृत समूह के पास होती है। उन्होंने इस समूह को तीन मुख्य क्षेत्रों के शीर्ष नेतृत्व से बना हुआ माना: प्रमुख राजनेता (राजनीतिक), बड़े निगमों के अधिकारी (आर्थिक) और उच्च पदस्थ अधिकारी (सैन्य)। मिल्स के अनुसार, ये तीनों क्षेत्र एक एकीकृत वर्ग के रूप में कार्य करते हैं जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय निर्णयों को नियंत्रित करते हैं, जो सामान्य जनता के प्रभाव से बाहर होते हैं।

116. (D) कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित होता है।
सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली की सबसे परिभाषित विशेषता कार्यपालिका के कार्यकाल की निश्चितता है। राष्ट्रपति का चुनाव एक निश्चित अवधि के लिए किया जाता है और उसे विधायी बहुमत द्वारा अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से सामान्यतः हटाया नहीं जा सकता है। इसमें कार्यपालिका विधायिका का हिस्सा नहीं होती, जिससे शक्तियों का स्पष्ट पृथक्करण बना रहता है। यह स्थिरता राष्ट्रपति को स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने और लंबी अवधि की नीतियां लागू करने की स्वायत्तता प्रदान करती है, जो संसदीय प्रणाली से भिन्न है।

117. (B) व्यवस्था को प्रभावित करने वाले अंतः-सामाजिक और बाह्य-सामाजिक पहलू।
डेविड ईस्टन के राजनीतिक व्यवस्था मॉडल में "पर्यावरण" का अर्थ उन सभी बाहरी और आंतरिक स्थितियों से है जो व्यवस्था को प्रभावित करती हैं। इसमें 'अंतः-सामाजिक' वातावरण (जैसे देश की अर्थव्यवस्था, संस्कृति और सामाजिक संरचना) और 'बाह्य-सामाजिक' वातावरण (जैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध, वैश्विक अर्थव्यवस्था और विदेशी राजनीति) दोनों शामिल हैं। राजनीतिक व्यवस्था इन पर्यावरणीय दबावों से आगत प्राप्त करती है और उनके उत्तर में निर्णय लेती है। व्यवस्था की स्थिरता इस बात पर निर्भर करती है कि वह इन चुनौतियों के साथ कितना सफल तालमेल बिठाती है।

118. (A) अल्पतंत्र का लौह नियम।
रॉबर्ट मिचल्स द्वारा प्रतिपादित 'अल्पतंत्र का लौह नियम' यह तर्क देता है कि बड़े पैमाने के संगठनों में सत्ता का केंद्रीकरण एक अपरिहार्य प्रक्रिया है। उनके अनुसार, "जो संगठन कहता है, वह अल्पतंत्र कहता है" क्योंकि संगठन चलाने के लिए

Downloaded from www.pdf.tube

135. (B) अभिजन शासन की दो शैलियाँ, जो क्रमशः बल और चतुराई पर आधारित हैं।
विल्फ्रेडो पेरेटो ने 'शेर' और 'लोमड़ी' के रूपकों का उपयोग उन दो प्रमुख तरीकों को समझाने के लिए किया जिनसे अभिजन सत्ता प्राप्त करते हैं और उसे बनाए रखते हैं। 'शेर' वे नेता हैं जो साहस, अखंडता और मुख्य रूप से बल प्रयोग के माध्यम से शासन करते हैं। इसके विपरीत, 'लोमड़ी' वे अभिजन हैं जो चालाकी, कूटनीति, हेरफेर और सौदेबाजी का सहारा लेते हैं। पेरेटो का मानना था कि समाज में शक्ति का संतुलन इन दो समूहों के संचलन पर निर्भर करता है, और एक सफल शासन को अक्सर इन दोनों गुणों के मिश्रण की आवश्यकता होती है।

136. (D) व्यक्तियों और समूहों का अवलोकन योग्य व्यवहार।
व्यवहारवादी क्रांति ने तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में एक आमूलचूल परिवर्तन किया, जिसने विद्वानों को औपचारिक कानूनों और संविधानों के अध्ययन से परे जाने के लिए प्रेरित किया। इस आंदोलन ने जोर दिया कि राजनीति को समझने के लिए राजनीतिक अभिनेताओं—जैसे मतदाता, नेता और हित समूह—के वास्तविक और दृश्य व्यवहार का विश्लेषण किया जाना चाहिए। वैज्ञानिक पद्धतियों और मात्रात्मक उपकरणों का उपयोग करते हुए, इसका उद्देश्य राजनीति के ऐसे सिद्धांत बनाना था जो तथ्यों पर आधारित हों और जिनका परीक्षण किया जा सके, जिससे यह विषय अधिक वस्तुनिष्ठ और यथार्थवादी बन गया।

137. (B) नियम निर्माण
संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक मॉडल में 'नियम निर्माण' को 'निर्गत कार्य' माना जाता है, न कि आगत कार्य। आगत कार्यों में हित प्रकटीकरण, हित समूहन, राजनीतिक समाजीकरण और राजनीतिक संचार शामिल हैं, क्योंकि ये समाज की मांगों और मूल्यों को व्यवस्था के भीतर पहुँचाते हैं। नियम निर्माण विधायिका का वह कार्य है जिसमें व्यवस्था समाज के लिए कानून और नीतियां तैयार करती है। यह अंतर राजनीतिक प्रक्रिया के प्रवाह को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जहाँ आगत इनपुट का काम करते हैं और नियम निर्माण उस प्रक्रिया का अंतिम परिणाम होता है।

138. (A) आधुनिकीकरण सामाजिक परिवर्तन है, जबकि विकास व्यवस्था की क्षमता है।
राजनीतिक आधुनिकीकरण और विकास के बीच सूक्ष्म अंतर यह है कि आधुनिकीकरण मुख्य रूप से उन व्यापक सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनों को संदर्भित करता है जो समाज के स्वरूप को बदलते हैं। दूसरी ओर, राजनीतिक विकास उस क्षमता और संस्थागत कुशलता को दर्शाता है जिसके माध्यम से राजनीतिक व्यवस्था इन परिवर्तनों से उत्पन्न नई मांगों और दबावों का सामना करती है। हंटिंगटन जैसे विद्वानों के अनुसार, आधुनिकीकरण के बिना भी विकास हो सकता है, लेकिन स्थिरता बनाए रखने के लिए राजनीतिक संस्थाओं की क्षमता का सामाजिक गतिशीलता के साथ तालमेल होना अनिवार्य है।

139. (A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं और कथन II, कथन I की सही व्याख्या है।
रॉबर्ट मिचल्स का 'अल्पतंत्र का लौह नियम' यह तथ्य प्रस्तुत करता है कि लोकतंत्र और बड़े पैमाने के संगठन व्यावहारिक रूप से असंगत हैं। उनका तर्क है कि जैसे-जैसे कोई संगठन बढ़ता है, उसे कुशल संचालन के लिए विशेषज्ञता और एक नेतृत्व की आवश्यकता होती है। इसके परिणामस्वरूप, निर्णय लेने की शक्ति अनिवार्य रूप से कुछ शीर्ष नेताओं के हाथों में सिमट जाती है, जबकि सामान्य सदस्य प्रभावहीन हो जाते हैं। अतः, संगठन का आकार बढ़ना ही उसके भीतर लोकतंत्र के क्षरण और अल्पतंत्र के उदय का प्राथमिक कारण बन जाता है।

140. (A) न्यायिक सक्रियता
जब कोई न्यायालय संविधान की व्याख्या इस प्रकार करता है कि वह केवल विवादों का समाधान ही नहीं करता, बल्कि सक्रिय रूप से नई नीतियों का निर्माण करता है या नागरिकों के लिए नए अधिकारों को मान्यता देती है, तो उसे 'न्यायिक सक्रियता' कहा जाता है। इसमें न्यायपालिका अक्सर विधायिका और कार्यपालिका के कार्यक्षेत्र में प्रवेश करती है ताकि सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया जा सके। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब सरकार के अन्य अंग अपनी भूमिका निभाने में विफल रहते हैं, जिससे न्यायपालिका लोकहित में निर्देश जारी कर शासन की कमियों को दूर करने का प्रयास करती है।

NODIA

141. (C) सूचना और संचार का प्रवाह
कार्ल डॉयच ने राजनीतिक प्रणालियों के अध्ययन के लिए 'संचार दृष्टिकोण' को विकसित किया। उन्होंने तर्क दिया कि राजनीति का सार शक्ति या संघर्ष नहीं, बल्कि सूचना का प्रभावी प्रसंस्करण और प्रेषण है। उनके अनुसार, एक राजनीतिक व्यवस्था एक जटिल संचार नेटवर्क की तरह कार्य करती है जहाँ प्राप्त प्रतिपुष्टि के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। यदि सूचना का प्रवाह बाधित होता है, तो व्यवस्था अपनी अनुकूलन क्षमता खो देती है। यह दृष्टिकोण किसी राज्य की स्थिरता और निर्णय लेने की कुशलता को उसकी संचार प्रणालियों की दक्षता के संदर्भ में मापने का प्रयास करता है।

142. (B) P-4, Q-3, R-2, S-1
शास्त्रीय और आधुनिक अभिजन सिद्धांतकारों ने शक्ति संरचना को समझने के लिए विविध विचार दिए हैं। विल्फ्रेडो पेरेटो ने अभिजनों के निरंतर संचलन का सिद्धांत दिया। गेटानो मोस्का ने शासक वर्ग की संगठनात्मक शक्ति और उसे वैध बनाने वाले 'राजनीतिक सूत्र' का विश्लेषण किया। रॉबर्ट मिचल्स ने संगठनों के भीतर 'अल्पतंत्र के लौह नियम' की पहचान की, जबकि सी. राइट मिल्स ने अमेरिकी समाज में कॉर्पोरेट, सैन्य और राजनीतिक क्षेत्रों से बने 'शक्ति अभिजन' के अस्तित्व को सिद्ध किया। ये सभी विचार आधुनिक समाज में सत्ता के केंद्रीकरण को स्पष्ट करते हैं।

143. (B) फ्रांसीसी राष्ट्रपति पद की संवैधानिक शक्तियां।
तुलनात्मक राजनीति का पारंपरिक दृष्टिकोण मुख्य रूप से औपचारिक-कानूनी संस्थाओं के अध्ययन पर केंद्रित होता है।

127. (D) विद्यालय का नागरिक शास्त्र पाठ्यक्रम
विद्यालय का नागरिक शास्त्र पाठ्यक्रम राजनीतिक समाजीकरण का एक औपचारिक और अत्यंत महत्वपूर्ण उदाहरण है। शिक्षा के माध्यम से राज्य सचेत रूप से अगली पीढ़ी को राष्ट्र के इतिहास, संवैधानिक मूल्यों, नागरिक अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। यह पाठ्यक्रम छात्रों के मन में राजनीतिक व्यवस्था के प्रति निष्ठा और सम्मान की भावना विकसित करता है। यह समाजीकरण का वह व्यवस्थित तरीका है जहाँ बच्चे पहली बार अपने व्यक्तिगत परिवेश से बाहर निकलकर एक व्यापक राजनीतिक समुदाय और शासन प्रणाली के बारे में सीखते हैं।

128. (C) संस्थागत ढांचा
कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों के बंटवारे और उनके परस्पर संबंधों का अध्ययन तुलनात्मक राजनीति के 'संस्थागत ढांचे' के अंतर्गत आता है। यह विश्लेषण इस बात पर केंद्रित होता है कि किसी देश का संविधान इन तीनों अंगों की सीमाओं और अधिकारों को कैसे परिभाषित करता है। इसमें शक्तियों के पृथक्करण, संसदीय उत्तरदायित्व और न्यायिक समीक्षा जैसे विषयों की जांच की जाती है। यह समझना आवश्यक है कि ये औपचारिक संस्थान शासन की स्थिरता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए एक-दूसरे के साथ किस प्रकार तालमेल बिठाते हैं।

129. (C) मिश्रित राजनीतिक संस्कृतियाँ।
'संकीर्ण-प्रजाभावी' या 'प्रजाभावी-सहभागी' जैसे शब्द उन समाजों को वर्णित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं जहाँ राजनीतिक संस्कृति परिवर्तन के दौर से गुजर रही होती है। आलमंड और वर्बा के अनुसार, शुद्ध राजनीतिक संस्कृतियाँ विरल होती हैं; अधिकांश देशों में नागरिकों की अभिवृत्तियों का एक 'मिश्रण' पाया जाता है। उदाहरण के लिए, एक समाज में कुछ लोग अभी भी संकीर्ण कबीलाई निष्ठाओं में बंधे हो सकते हैं, जबकि अन्य सक्रिय भागीदार बन रहे हों। यह संक्रमणकालीन विशेषता यह समझने में मदद करती है कि समाज पारंपरिक ढांचे से आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था की ओर कैसे बढ़ता है।

130. (A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।
तुलनात्मक राजनीति के आधुनिक और पारंपरिक चरणों के बीच का अंतर उनके दृष्टिकोण में स्पष्ट है। पारंपरिक अनुशासन मुख्य रूप से वर्णनात्मक और आदर्शात्मक था, जो केवल कानूनी संस्थानों के विवरण और 'आदर्श शासन' की चर्चा तक सीमित रहता था। इसके विपरीत, व्यवहारवादी क्रांति के बाद आधुनिक तुलनात्मक राजनीति 'व्याख्यात्मक' और वैज्ञानिक बन गई है। अब इसका उद्देश्य केवल संस्थानों का वर्णन करना नहीं, बल्कि आनुभविक डेटा के आधार पर राजनीतिक व्यवहार के कारणों और परिणामों को समझना तथा सिद्धांतों का निर्माण करना है, जो वैश्विक तुलना को सक्षम बनाता है।

131. (B) वह सिद्धांत या विचारधारा जो अभिजन के शासन को वैध बनाती है।
गेटानो मोस्का ने 'राजनीतिक सूत्र' की अवधारणा यह समझाने के लिए दी थी कि एक छोटा अल्पसंख्यक शासक वर्ग बहुसंख्यक जनता पर अपनी सत्ता को कैसे वैध ठहराता है। यह सूत्र वह कानूनी या नैतिक तर्क होता है—जैसे दैवीय अधिकार, राष्ट्रवाद या लोकतंत्र—जिस पर समाज विश्वास करता है। मोस्का का मानना था कि कोई भी शासक केवल शारीरिक बल के आधार पर टिक नहीं सकता; उसे अपनी आज्ञाकारिता सुनिश्चित करने के लिए एक ऐसी विचारधारा की आवश्यकता होती है जो शासन को न्यायसंगत और उचित सिद्ध कर सके।

132. (A) पर्यावरण के साथ प्रक्रिया और अंतःक्रिया पर जोर देने वाला एक गतिशील मॉडल प्रदान करना।
डेविड ईस्टन द्वारा प्रतिपादित व्यवस्था दृष्टिकोण का सबसे महत्वपूर्ण योगदान राजनीति को एक गतिशील और परस्पर निर्भर प्रक्रिया के रूप में देखना था। इसने राजनीति के अध्ययन को केवल स्थिर कानूनों और संस्थानों से हटाकर आगत और निर्गत के निरंतर चक्र पर केंद्रित किया। यह मॉडल यह स्पष्ट करता है कि राजनीतिक व्यवस्था अपने बाहरी सामाजिक और आर्थिक पर्यावरण के प्रति कैसे प्रतिक्रिया करती है और जीवित रहने के लिए संतुलन कैसे बनाती है। इसने राजनीति विज्ञान को एक समग्र और वैज्ञानिक ढांचा प्रदान किया जो विविध प्रणालियों की तुलना में सहायक है।

133. (C) अर्ध-राष्ट्रपति प्रणाली
अर्ध-राष्ट्रपति प्रणाली वह शासन व्यवस्था है जिसमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों के पास महत्वपूर्ण कार्यकारी शक्तियां होती हैं। इसमें राष्ट्रपति सीधे जनता द्वारा निर्वाचित होता है और राष्ट्राध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, जबकि प्रधानमंत्री सरकार का नेतृत्व करता है और उसे संसद का विश्वास प्राप्त होना अनिवार्य है। यह प्रणाली फ्रांस की विशेषता है। यह राष्ट्रपति प्रणाली की स्थिरता और संसदीय प्रणाली की जवाबदेही का एक अनोखा मिश्रण प्रस्तुत करती है, जहाँ कार्यकारी शक्ति का प्रयोग दो अलग-अलग केंद्रों द्वारा किया जाता है, जो संतुलन बनाए रखते हैं।

134. (B) वे कौन सी राजनीतिक प्रक्रियाएं हैं जिनके माध्यम से समाज समय के साथ बदलते हैं?
राजनीतिक विकास के अध्ययन का मुख्य केंद्र यह समझना है कि समय के साथ राजनीतिक व्यवस्थाओं की संरचना और क्षमता में कैसे परिवर्तन आता है। यह विषय केवल स्थिर संस्थानों का वर्णन नहीं करता, बल्कि उन प्रक्रियाओं का विश्लेषण करता है जो समाज को पारंपरिक से आधुनिक शासन की ओर ले जाती हैं। इसमें राजनीतिक संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण, नागरिकों की बढ़ती भागीदारी और जटिल समस्याओं को हल करने की राज्य की शक्ति में वृद्धि जैसे प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं। इसका उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि परिवर्तन के दबाव में राजनीतिक व्यवस्थाएं स्थिरता और विकास कैसे प्राप्त करती हैं।

Click Here to Buy book on Amazon

राज्य का अस्तित्व वर्ग संघर्ष को दबाने और यथास्थिति बनाए रखने के लिए होता है। साम्यवादी विचारधारा के अनुसार, जब समाज में वर्ग समाप्त हो जाएंगे, तब राज्य की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी और वह स्वतः विलुप्त हो जाएगा।

152. (B) कानूनों को निरस्त करने या नीति में हस्तक्षेप करने की न्यायपालिका की इच्छा।
तुलनात्मक संदर्भ में, 'न्यायिक सक्रियता' का तात्पर्य न्यायालयों की उस प्रवृत्ति से है जहाँ वे केवल कानूनों की व्याख्या ही नहीं करतीं, बल्कि सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए विधायी और कार्यकारी निर्णयों में सीधे हस्तक्षेप करती हैं। इसमें न्यायपालिका अक्सर अपने पारंपरिक क्षेत्राधिकार से बाहर निकलकर जनहित याचिकाओं के माध्यम से नई नीतियां बनाने या सरकार को निर्देश देने की इच्छा प्रदर्शित करती है। यह स्थिति तब महत्वपूर्ण हो जाती है जब शासन के अन्य अंग निष्क्रिय होते हैं, जिससे न्यायपालिका लोकहित के रक्षक के रूप में एक अग्रणी भूमिका निभाने लगती है।

153. (B) राजनीतिक मूल्यों को सीखना, जबकि भर्ती भूमिकाओं के लिए लोगों का चयन करने के बारे में है।
राजनीतिक समाजीकरण और राजनीतिक भर्ती दो अलग-अलग प्रकार्यात्मक प्रक्रियाएं हैं। समाजीकरण वह व्यापक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समाज के सभी नागरिक बचपन से ही राजनीति के प्रति अपने मूल्यों, विश्वासों और अभिवृत्तियों को सीखते हैं। इसके विपरीत, राजनीतिक भर्ती एक संकीर्ण प्रक्रिया है जो विशेष रूप से उन व्यक्तियों के चयन पर केंद्रित होती है जो राजनीतिक व्यवस्था के भीतर सक्रिय भूमिकाएं, जैसे नेतृत्व या प्रशासनिक उत्तरदायित्व संभालेंगे। संक्षेप में, समाजीकरण व्यक्ति को एक जागरूक नागरिक बनाता है, जबकि भर्ती उसे एक सक्रिय राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में चुनती है।

154. (B) यह चुनना कि नेताओं का कौन सा दल शासन करेगा।
'प्रतिस्पर्धी अभिजनवाद' के सिद्धांत के अनुसार, जोसेफ शुम्पेटर जैसे विद्वानों का मानना है कि आधुनिक लोकतंत्र में आम नागरिक की भूमिका काफी सीमित होती है। यहाँ नागरिक सीधे नीति निर्माण में भाग नहीं लेते, बल्कि उनकी प्राथमिक भूमिका केवल समय-समय पर होने वाले चुनावों में भाग लेकर यह तय करना है कि प्रतिस्पर्धी अभिजन समूहों में से कौन सा दल सत्ता संभालेगा। लोकतंत्र को यहाँ केवल एक 'प्रक्रियात्मक विधि' माना गया है, जहाँ जनता को अपने शासक चुनने का अवसर मिलता है, लेकिन शासन की वास्तविक बागडोर हमेशा चुने हुए अभिजनों के हाथों में ही रहती है।

155. (A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।
विधायी संरचना का चयन अक्सर किसी देश की प्रशासनिक व्यवस्था और क्षेत्रीय विविधता पर निर्भर करता है। एकसदनीय विधायिका सामान्यतः उन छोटे और एकात्मक राज्यों में पाई जाती है जहाँ जनसंख्या समरूप होती है और शक्ति का केंद्रीकरण सरल होता है। इसके विपरीत, द्विसदनीय विधायिका विशेष रूप से उन बड़े और संघीय राज्यों में आवश्यक मानी जाती है जहाँ शक्तियों को केंद्र और राज्यों के बीच साझा किया जाता है। दूसरा सदन यहाँ राज्यों के हितों का प्रतिनिधित्व करने और विधायी प्रक्रिया में आवश्यक संतुलन व ठहराव सुनिश्चित करने के लिए एक रक्षक के रूप में कार्य करता है।

156. (A) विशेष से सामान्य की ओर।
तुलनात्मक राजनीति के विकास की यात्रा 'विशेष' से 'सामान्य' की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाती है। प्रारंभ में, यह विषय केवल कुछ विशेष पश्चिमी देशों की सरकारों के अलग-अलग और विस्तृत वर्णन तक ही सीमित था। आधुनिक समय में, विद्वानों का ध्यान अब ऐसी सामान्य अवधारणाओं और व्यापक सिद्धांतों के निर्माण पर केंद्रित हो गया है जिन्हें दुनिया की किसी भी राजनीतिक व्यवस्था पर लागू किया जा सके। इस परिवर्तन ने तुलनात्मक राजनीति को एक अधिक विश्लेषणात्मक और वैज्ञानिक अनुशासन बनाया है, जो विशिष्ट तथ्यों के बजाय वैश्विक स्तर पर मौजूद सामान्य पैटर्न को समझाने का प्रयास करता है।

157. (B) मूल्यों
डेविड ईस्टन की राजनीति की प्रसिद्ध परिभाषा के अनुसार, राजनीति "समाज के लिए मूल्यों का आधिकारिक आवंटन" है। यहाँ 'मूल्य' का अर्थ केवल नैतिक विचार नहीं, बल्कि समाज के वे महत्वपूर्ण संसाधन, अधिकार और लाभ हैं जिनकी मांग अधिक और उपलब्धता कम होती है। 'आधिकारिक आवंटन' का तात्पर्य है कि सरकार द्वारा लिए गए निर्णय कानूनी रूप से बाध्यकारी होते हैं और उनका पालन समाज के सभी सदस्यों को करना पड़ता है। यह परिभाषा राजनीति को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में देखती है जहाँ सत्ता का उपयोग समाज की प्राथमिकताओं और पुरस्कारों के वितरण के लिए किया जाता है।

158. (D) कार्यकारी और विधायी शाखाएं परस्पर संबद्ध और एक-दूसरे पर निर्भर हैं।
संसदीय प्रणाली में 'शक्तियों के संलयन' का मूल अर्थ कार्यपालिका और विधायिका के बीच गहरा समन्वय और परस्पर निर्भरता है। इस व्यवस्था में, सरकार के सभी सदस्य अनिवार्य रूप से संसद के सदस्य होते हैं। मंत्रिमंडल अपने कार्यों के लिए संसद के प्रति सीधे उत्तरदायी होता है और वह तब तक ही सत्ता में रह सकता है जब तक उसे संसद के बहुमत का विश्वास प्राप्त हो। यह संलयन शासन में एकता लाता है और यह सुनिश्चित करता है कि कार्यपालिका अपनी नीतियों के लिए जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रति निरंतर जवाबदेह बनी रहे।

159. (A) यह मानना कि समाज एक पूर्व निर्धारित और निश्चित अंतिम बिंदु की ओर बढ़ते हैं।
राजनीतिक आधुनिकीकरण के शुरुआती सिद्धांतों की प्रमुख आलोचना इस 'एकरेखीय' धारणा के लिए की गई कि सभी समाजों को अनिवार्य रूप से पश्चिमी लोकतांत्रिक और औद्योगिक मॉडल की ओर ही बढ़ना है। आलोचकों का तर्क था कि इन सिद्धांतों ने विकास को एक पूर्व निर्धारित प्रक्रिया मान लिया और अन्य सांस्कृतिक पथों की उपेक्षा की। इसके अतिरिक्त, यह भी माना गया कि आर्थिक प्रगति हमेशा स्थिरता

NODIA

अतः, इस दृष्टिकोण का उपयोग करने वाला विद्वान फ्रांसीसी राष्ट्रपति पद की संवैधानिक शक्तियों, लिखित कानूनों और औपचारिक अधिकारों के विश्लेषण को प्राथमिकता देगा। यह दृष्टिकोण इस बात पर कम ध्यान देता है कि राष्ट्रपति वास्तव में व्यवहार में उन शक्तियों का उपयोग कैसे करता है या चुनावी राजनीति उसे कैसे प्रभावित करती है। इसके बजाय, इसका मुख्य केंद्र संविधान के पाठ और कानूनी प्रावधानों के माध्यम से सरकार के ढांचे को समझना और उसका वर्णन करना होता है।

144. (A) नागरिक संस्कृति
'नागरिक संस्कृति' की अवधारणा गैब्रियल आलमंड और सिडनी वर्बा द्वारा प्रस्तुत की गई थी। उनका तर्क था कि एक स्थिर और सफल लोकतंत्र के लिए नागरिकों में केवल उच्च राजनीतिक भागीदारी ही पर्याप्त नहीं है। इसके बजाय, इसमें सरकार के प्रति सम्मानजनक आज्ञाकारिता और स्थानीय पहचानों का एक संतुलित मिश्रण होना चाहिए। यह संस्कृति सरकार को प्रभावी ढंग से शासन करने की अनुमति देती है और साथ ही यह भी सुनिश्चित करती है कि नागरिक आवश्यकतानुसार उस पर नियंत्रण रख सकें, जिससे लोकतंत्र का अस्तित्व बना रहता है।

145. (D) 1, 2 और 3
आधुनिक शासन व्यवस्था में सरकार के तीनों अंग—विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका—अपने विशिष्ट कार्यों के माध्यम से राज्य का संचालन करते हैं। विधायिका का प्राथमिक उत्तरदायित्व समाज के लिए नियमों और कानूनों का निर्माण करना है। कार्यपालिका का कार्य उन कानूनों को प्रशासनिक तंत्र के माध्यम से लागू करना और शासन का दैनिक प्रबंधन करना है। न्यायपालिका इन कानूनों की व्याख्या करती है और विवादों का समाधान करते हुए यह सुनिश्चित करती है कि न्याय का शासन बना रहे। इन तीनों अंगों का संतुलित समन्वय ही किसी भी राजनीतिक व्यवस्था की प्रभावशीलता और स्थिरता का आधार होता है।

146. (A) संसदीय प्रणाली
'अविश्वास प्रस्ताव' संसदीय शासन प्रणाली का एक अत्यंत शक्तिशाली और अनिवार्य संवैधानिक उपकरण है। यह विधायिका को कार्यपालिका पर प्रभावी नियंत्रण रखने की शक्ति देता है। इस व्यवस्था में, यदि संसद का निचला सदन सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देता है, तो प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल को तत्काल त्यागपत्र देना पड़ता है। यह सुनिश्चित करता है कि कार्यपालिका अपनी सत्ता के लिए सदैव निर्वाचित प्रतिनिधियों के विश्वास और बहुमत पर निर्भर रहे। यह प्रणाली सरकार की जवाबदेही को निरंतर बनाए रखने और सत्ता के दुरुपयोग को रोकने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

147. (C) उदासीन, अक्षम और असंगठित।
अभिजनवादी सिद्धांत की एक मूल मान्यता यह है कि समाज की विशाल बहुसंख्यक जनता या जनसमूह राजनीतिक रूप से उदासीन, अक्षम और असंगठित होता है। इस सिद्धांत के अनुसार, सामान्य नागरिक अक्सर महत्वपूर्ण मुद्दों की गहरी समझ नहीं रखते और शासन करने की कला से अनभिज्ञ होते हैं। इसके विपरीत, अल्पसंख्यक अभिजन वर्ग संगठित, शिक्षित और संसाधनों से संपन्न होता है, जो उन्हें सत्ता पर नियंत्रण बनाए रखने के योग्य बनाता है। इसी कारण अभिजनवादी यह तर्क देते हैं कि शासन हमेशा एक छोटे समूह द्वारा ही संचालित होता है, चाहे दिखावा लोकतंत्र का ही क्यों न हो।

148. (B) अस्तित्व बनाए रखने और खुद को संरक्षित करने के लिए।
डेविड ईस्टन के व्यवस्था दृष्टिकोण के अनुसार, एक राजनीतिक व्यवस्था निरंतर पर्यावरण से आने वाले विक्षोभों, तनावों और मांगों का सामना करती है। इस व्यवस्था का प्राथमिक लक्ष्य इन चुनौतियों का समाधान करना और स्वयं के अस्तित्व को बनाए रखना है। व्यवस्था इन विक्षोभों पर प्रतिक्रिया करते हुए अपने ढांचे और प्रक्रियाओं में आवश्यक बदलाव करती है ताकि वह पूरी तरह चरमरा न जाए। यह निरंतर अनुकूलन और आत्म-संरक्षण की प्रक्रिया ही राजनीतिक व्यवस्था को गतिशील बनाती है और उसे लंबे समय तक क्रियाशील रहने में मदद करती है।

149. (C) विभिन्न जातीय या क्षेत्रीय समूहों को एक एकल राष्ट्रीय पहचान में एकीकृत करना।
राजनीतिक विकास में 'पहचान का संकट' उस मौलिक चुनौती को संदर्भित करता है जहाँ किसी देश के नागरिक स्वयं को एक साझा राष्ट्रीय समुदाय के हिस्से के रूप में महसूस नहीं करते हैं। यह स्थिति अक्सर उन नए स्वतंत्र राज्यों में देखी जाती है जहाँ लोग राष्ट्रीय पहचान के बजाय अपनी संकीर्ण जातीय, भाषाई या क्षेत्रीय पहचानों के प्रति अधिक निष्ठा रखते हैं। सफल विकास के लिए यह आवश्यक है कि सरकार एक ऐसी समावेशी भावना विकसित करे जिससे सभी विविध समूह एक राष्ट्र के रूप में एकताबद्ध महसूस करें। इसके बिना राष्ट्र-निर्माण की प्रक्रिया अधूरी बनी रहती है।

150. (A) 2, 1, 3, 4
तुलनात्मक राजनीति के विभिन्न दृष्टिकोणों का उदय एक निश्चित ऐतिहासिक क्रम में हुआ है। सर्वप्रथम पारंपरिक संस्थावाद का युग था जो केवल औपचारिक कानूनों तक सीमित था। इसके बाद 1950 के दशक में वैज्ञानिक और समग्र विश्लेषण के लिए डेविड ईस्टन का व्यवस्था दृष्टिकोण आया। इसके तुरंत बाद गैब्रियल आलमंड द्वारा संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक मॉडल विकसित किया गया जो अधिक व्यावहारिक तुलना प्रदान करता था। अंततः 1960 के दशक के उत्तरार्ध में उत्तर-व्यवहारवाद का उदय हुआ, जिसने तकनीकी शुद्धता के स्थान पर सामाजिक प्रासंगिकता और मानवीय मूल्यों को प्राथमिकता देने का आह्वान किया।

151. (C) राज्य वर्गों के बीच एक तटस्थ मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है।
मार्क्सवादी दृष्टिकोण इस उदारवादी धारणा का कड़ा विरोध करता है कि राज्य एक तटस्थ निकाय है जो समाज के सभी वर्गों के सामान्य कल्याण के लिए कार्य करता है। इसके विपरीत, मार्क्सवाद यह प्रतिपादित करता है कि राज्य अनिवार्य रूप से 'अधिसंरचना' का एक हिस्सा है और यह आर्थिक रूप से प्रभावी शासक वर्ग के हितों को सुरक्षित रखने का एक साधन मात्र है।

Downloaded from www.pdf.tube

आवश्यक विशेषज्ञता और प्रशासनिक कौशल के कारण नेतृत्व का एक छोटा समूह स्थायी और शक्तिशाली बन जाता है। आम सदस्य धीरे-धीरे अपनी भागीदारी खो देते हैं और पूरी तरह से नेताओं पर निर्भर हो जाते हैं। यह नियम बताता है कि पूर्ण आंतरिक लोकतंत्र को बनाए रखना किसी भी बड़े संस्थान के लिए व्यावहारिक रूप से असंभव है।

119. (A) P-2, Q-1, R-4, S-3
विभिन्न देशों की राजनीतिक प्रणालियाँ अपनी विशिष्ट विशेषताओं के लिए जानी जाती हैं। यूनाइटेड किंगडम में संसदीय संप्रभुता का सिद्धांत प्रचलित है जहाँ संसद सर्वोच्च है। संयुक्त राज्य अमेरिका में शक्तियों का सख्त पृथक्करण और नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था लागू है। फ्रांस अर्ध-राष्ट्रपतिवाद का एक प्रमुख उदाहरण है जहाँ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों के पास कार्यकारी शक्तियां होती हैं। जर्मनी में 'रचनात्मक अविश्वास प्रस्ताव' का उपयोग किया जाता है, जो सरकार को अस्थिर होने से रोकने के लिए केवल तभी हटाने की अनुमति देता है जब वैकल्पिक नेतृत्व तैयार हो।

120. (D) यह स्थिर होती है और समय के साथ बदलती नहीं है।
राजनीतिक संस्कृति के बारे में यह धारणा अनुचित है कि यह पूरी तरह स्थिर रहती है और बदलती नहीं है। वास्तव में, राजनीतिक संस्कृति गतिशील होती है और ऐतिहासिक घटनाओं, आर्थिक परिवर्तनों, शिक्षा के प्रसार और नई पीढ़ियों के अनुभवों के साथ समय के साथ विकसित होती रहती है। हालांकि इसके कुछ मूल तत्व दीर्घकालिक हो सकते हैं, लेकिन सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों में बदलाव नागरिकों के विश्वासों और मूल्यों को प्रभावित करता है। इसे सर्वेक्षणों के माध्यम से मापा जा सकता है और यह किसी भी राजनीतिक व्यवस्था की दीर्घकालिक स्थिरता का मुख्य आधार होती है।

121. (C) एशिया और अफ्रीका में नए स्वतंत्र राज्यों का उदय।
द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में अभूतपूर्व विस्तार का मुख्य कारण वि-औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया थी। एशिया और अफ्रीका में बड़ी संख्या में नए राष्ट्रों के स्वतंत्र होने से राजनीति विज्ञानियों के सामने ऐसी प्रणालियाँ आईं जो पश्चिमी मॉडलों से बिल्कुल भिन्न थीं। इन नए राज्यों की विविध राजनीतिक चुनौतियों ने विद्वानों को नए सिद्धांतों और उपकरणों को विकसित करने के लिए प्रेरित किया। इसने तुलनात्मक राजनीति को एक वैश्विक और अधिक वैज्ञानिक अनुशासन में बदल दिया, जो केवल यूरोप तक सीमित नहीं रहा।

122. (A) द्विसदनीय
जिस विधायी प्रणाली में दो पृथक सदन या कक्ष होते हैं, उसे द्विसदनीय विधायिका कहा जाता है। सामान्यतः इसमें एक 'निचला सदन' (जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला) और एक 'ऊपरी सदन' (राज्यों या विशिष्ट हितों का प्रतिनिधित्व करने वाला) शामिल होता है। यह व्यवस्था शक्तियों के संतुलन को बनाए रखने और विधान प्रक्रिया में अधिक गहराई प्रदान करने के लिए अपनाई जाती है। संघीय देशों में यह अत्यंत लोकप्रिय है क्योंकि यह क्षेत्रीय हितों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी आवाज देने में मदद करती है और जल्दबाजी में कानून पारित होने की संभावना को कम करती है।

123. (A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं और कथन II, कथन I की सही व्याख्या है।
मार्क्सवादी दृष्टिकोण की अक्सर आलोचना इसलिए की जाती है क्योंकि यह आर्थिक कारकों को समाज के सभी परिवर्तनों का एकमात्र कारण मानता है, जिसे 'आर्थिक नियतिवाद' कहा जाता है। कार्ल मार्क्स का तर्क था कि समाज का आर्थिक आधार ही उसकी कानूनी और राजनीतिक अधिसंरचना को पूरी तरह से आकार देता है। इसका अर्थ है कि राजनीतिक विचार, कानून और सरकारी संस्थान केवल आर्थिक शक्ति संबंधों का प्रतिबिंब मात्र हैं। आलोचकों का मानना है कि यह दृष्टिकोण संस्कृति, विचारधारा और स्वायत्त राजनीतिक इच्छाशक्ति की भूमिका को कम करके आंकता है।

124. (B) सरकार के समक्ष मांगों और जरूरतों को व्यक्त करना।
संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक विश्लेषण में 'हित प्रकटीकरण' एक प्रारंभिक और महत्वपूर्ण आगत कार्य है। यह वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समाज के विभिन्न नागरिक समूह, श्रमिक संघ और दबाव समूह अपनी विशिष्ट मांगों, चिंताओं और आवश्यकताओं को औपचारिक रूप से राजनीतिक व्यवस्था के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। यह कार्य सुनिश्चित करता है कि नीति निर्माताओं को जनता की समस्याओं और अपेक्षाओं की सही जानकारी मिले। सफल हित प्रकटीकरण राजनीतिक व्यवस्था को समाज के प्रति उत्तरदायी और संवेदनशील बनाए रखने में मदद करता है, जिससे शासन की प्रभावशीलता बढ़ती है।

125. (C) 'जनता द्वारा शासन' का सिद्धांत।
लोकतंत्र का अभिजनवादी सिद्धांत शास्त्रीय लोकतंत्र की उस मूल धारणा को चुनौती देता है जो यह मानती है कि शक्ति वास्तव में जनता के हाथों में होती है। अभिजन सिद्धांतकारों का तर्क है कि आधुनिक समाज की जटिलता और विशालता के कारण प्रत्यक्ष जन शासन एक मिथक है। उनके अनुसार, वास्तविक निर्णय हमेशा एक छोटे संगठित समूह द्वारा ही लिए जाते हैं। इस प्रकार, यह सिद्धांत लोकतंत्र को 'जनता के शासन' के बजाय अभिजनों के बीच सत्ता के लिए एक प्रतिस्पर्धी संघर्ष के रूप में पुनर्परिभाषित करता है, जहाँ जनता की भूमिका केवल चुनाव तक सीमित है।

126. (A) धन, वस्तुओं और सेवाओं के आधिकारिक आवंटन के संबंध में संघर्ष।
राजनीतिक विकास की प्रक्रिया में 'वितरण संकट' तब उत्पन्न होता है जब सरकार समाज के विभिन्न वर्गों के बीच धन, संसाधनों और सेवाओं के न्यायसंगत आवंटन की बढ़ती मांगों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन नहीं कर पाती है। जैसे-जैसे राजनीतिक भागीदारी बढ़ती है, हाशिए पर रहने वाले समूह और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग सरकार से अधिक लाभ और सामाजिक सुरक्षा की अपेक्षा करने लगते हैं। यदि राज्य इन संसाधनों के वितरण के लिए कुशल तंत्र विकसित करने में विफल रहता है, तो इससे सामाजिक असंतोष और राजनीतिक अस्थिरता पैदा होती है, जो विकास को बाधित करती है।

NODIA

नहीं लाती, बल्कि कभी-कभी यह सामाजिक तनाव और अव्यवस्था का कारण भी बन सकती है। इस आलोचना ने बाद में अधिक लचीले और विविधतापूर्ण विकास सिद्धांतों के उदय का मार्ग प्रशस्त किया।

160. (B) एक सहभागी राजनीतिक संस्कृति।
एक 'सहभागी' राजनीतिक संस्कृति वह होती है जहाँ नागरिक अपनी राजनीतिक व्यवस्था के प्रति अत्यधिक जागरूक होते हैं और वे आगत प्रक्रियाओं, जैसे चुनाव और नीति निर्माण में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। ऐसे समाजों में लोग यह विश्वास करते हैं कि वे अपने कार्यों के माध्यम से सरकारी निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं और उनमें उच्च स्तर की राजनीतिक प्रभावकारिता होती है। यह संस्कृति लोकतंत्र की सफलता के लिए अत्यंत अनुकूल मानी जाती है क्योंकि यह शासन को जनमत के प्रति संवेदनशील बनाती है और नागरिकों को व्यवस्था का सक्रिय भागीदार बनाती है।

161. (C) गेटानो मोस्का
'राजनीतिक सूत्र' की अवधारणा शास्त्रीय अभिजन सिद्धांतकार गेटानो मोस्का द्वारा प्रतिपादित की गई थी। उनका तर्क था कि कोई भी अल्पसंख्यक शासक वर्ग केवल बल के प्रयोग से लंबे समय तक शासन नहीं कर सकता। उसे अपनी सत्ता को समाज की नज़रों में उचित और नैतिक सिद्ध करने के लिए एक तर्कसंगत आधार की आवश्यकता होती है, जिसे उन्होंने 'राजनीतिक सूत्र' कहा। यह सूत्र दैवीय इच्छा, लोकतंत्र या राष्ट्रवाद जैसी मान्यताओं पर आधारित हो सकता है जो शासितों को आज्ञा मानने के लिए मानसिक रूप से तैयार करता है और शासन को वैधता प्रदान करता है।

162. (B) यह समझना कि विभिन्न प्रणालियों में संरचनाएं आवश्यक कार्य कैसे निष्पादित करती हैं।
संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना है कि विभिन्न राजनीतिक प्रणालियाँ, अपनी औपचारिक संरचनाओं में भिन्नता के बावजूद, व्यवस्था को जीवित रखने के लिए आवश्यक कार्यों को कैसे पूरा करती हैं। यह दृष्टिकोण मानता है कि प्रत्येक सफल व्यवस्था में कुछ प्रकार्य अनिवार्य होते हैं। इसका लाभ यह है कि इसके माध्यम से हम एक पश्चिमी लोकतंत्र और एक पारंपरिक समाज की तुलना इस आधार पर कर सकते हैं कि वे अपनी विशिष्ट संस्थाओं के माध्यम से इन सार्वभौमिक आवश्यकताओं को कैसे पूरा करते हैं। यह तुलनात्मक विश्लेषण को अधिक वैज्ञानिक और व्यावहारिक बनाता है।

163. (D) 1, 2 और 3
तुलनात्मक राजनीति में यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका की व्यवस्थाएं दो अलग-अलग मॉडलों का प्रतिनिधित्व करती हैं। यूनाइटेड किंगडम में कार्यपालिका विधायिका के भीतर से ही निकलती है और उसके प्रति उत्तरदायी होती है, जबकि अमेरिका में राष्ट्रपति और संसद के बीच शक्तियों का सख्त पृथक्करण होता है। इसके अतिरिक्त, यूनाइटेड किंगडम में 'संसदीय संप्रभुता' के कारण न्यायालयों की शक्तियां सीमित हैं, जबकि अमेरिका में 'न्यायिक समीक्षा' अत्यंत शक्तिशाली है। ये दोनों व्यवस्थाएं दर्शाती हैं कि कैसे विभिन्न लोकतांत्रिक संरचनाएं शक्ति के संतुलन और जवाबदेही के लिए अलग-अलग तरीकों का उपयोग करती हैं।

164. (B) सरकार को व्यवस्था में सम्मिलित होने के लिए सामाजिक समूहों से अत्यधिक मांगों का सामना करना पड़ता है।
विकास साहित्य में 'भागीदारी का संकट' उस स्थिति को दर्शाता है जब समाज के नए सामाजिक और आर्थिक समूह राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल होने के लिए तीव्र मांगें करने लगते हैं। यह स्थिति अक्सर तब उत्पन्न होती है जब आधुनिकीकरण के कारण लोगों में जागरूकता बढ़ती है। यदि विद्यमान राजनीतिक संस्थाएं इन समूहों को व्यवस्थित रूप से शामिल करने में विफल रहती हैं, तो यह तनाव सामाजिक विद्रोह और अस्थिरता का कारण बन सकता है। सफल राजनीतिक विकास के लिए इन बढ़ती मांगों को समय पर और शांतिपूर्ण ढंग से आत्मसात करना राज्य के लिए एक बड़ी चुनौती होती है।

165. (B) कार्यसूची-निर्धारण
जनसंचार माध्यमों की 'कार्यसूची-निर्धारण' की भूमिका इस तथ्य पर आधारित है कि वे किन समाचारों और मुद्दों को प्रमुखता से दिखाते हैं। जब मीडिया किसी विशेष विषय पर बार-बार चर्चा करता है, तो जनता और सरकार उसे महत्वपूर्ण मानने लगते हैं। इस प्रकार, मीडिया प्रत्यक्ष रूप से यह तय नहीं करता कि लोग क्या सोचें, लेकिन वह यह जरूर तय करता है कि वे किस बारे में सोचें। यह शक्ति राजनीतिक विमर्श को दिशा देने और सार्वजनिक प्राथमिकताओं को आकार देने में अत्यंत प्रभावशाली होती है, जो अंततः सरकारी नीतियों को प्रभावित कर सकती है।

166. (A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं और कथन II, कथन I की सही व्याख्या है।
व्यवहारवादी दृष्टिकोण ने 20वीं सदी के मध्य में राजनीति विज्ञान को एक ठोस वैज्ञानिक आधार प्रदान करने का प्रयास किया। इसने दार्शनिक चिंतन और केवल कानूनी विवरणों के स्थान पर तथ्यों और अवलोकन योग्य व्यवहार पर जोर दिया। इस आंदोलन का मुख्य तर्क यह था कि यदि हम राजनीतिक अभिनेताओं के व्यवहार का सांख्यिकीय और मात्रात्मक विश्लेषण करें, तो हम राजनीति के ऐसे सामान्य सिद्धांत विकसित कर सकते हैं जिनका वैज्ञानिक परीक्षण संभव हो। इस बदलाव ने तुलनात्मक राजनीति को अधिक वस्तुनिष्ठ और यथार्थवादी बनाया।

167. (D) हित-समूहन
गैब्रियल आलमंड के संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक मॉडल के अनुसार, 'हित समूहन' को एक आगत कार्य माना जाता है, न कि निर्गत कार्य। निर्गत कार्यों में नियम निर्माण, नियम अनुप्रयोग और नियम अधिनिर्णयन शामिल हैं, क्योंकि ये वे आधिकारिक क्रियाएं हैं जो सरकार द्वारा समाज के लिए की जाती हैं। इसके विपरीत, हित समूहन वह प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न मांगों को एकीकृत करके राजनीतिक दलों द्वारा नीतिगत विकल्पों के रूप में व्यवस्था के भीतर भेजा जाता है। यह भेद स्पष्ट करता है

Click Here to Buy book on Amazon

कि कैसे समाज की इच्छाएं व्यवस्था में प्रवेश करती हैं और फिर आधिकारिक निर्णयों के रूप में बाहर आती हैं।

168. (A) शक्ति अभिजन आधुनिक समाज के विशिष्ट क्षेत्रों से बना एक अधिक एकीकृत समूह है।
सी. राइट मिल्स द्वारा प्रस्तुत 'शक्ति अभिजन' की अवधारणा शास्त्रीय अभिजनवाद से इस मायने में अलग है कि यह आधुनिक औद्योगिक समाज की विशिष्ट संरचना पर आधारित है। मिल्स का तर्क था कि 20वीं सदी के अमेरिका में शक्ति केवल व्यक्तिगत गुणों पर नहीं, बल्कि कॉर्पोरेट, सैन्य और राजनीतिक संस्थानों के शीर्ष पदों के बीच मौजूद गहरे तालमेल पर निर्भर करती है। ये तीन क्षेत्रों के नेता एक एकीकृत वर्ग के रूप में कार्य करते हैं, जो शास्त्रीय अभिजनवादियों द्वारा वर्णित केवल एक संगठित अल्पसंख्यक की तुलना में कहीं अधिक संस्थागत और शक्तिशाली होते हैं।

169. (B) P-2, Q-4, R-1, S-3
लुसियन पाई द्वारा पहचाने गए राजनीतिक विकास के संकट राष्ट्र-निर्माण की विभिन्न चुनौतियों को दर्शाते हैं। पहचान का संकट एक साझा राष्ट्रीय गौरव की भावना पैदा करने से संबंधित है। वैधता का संकट शासन करने के सरकार के नैतिक अधिकार की जन-स्वीकृति सुनिश्चित करने की चुनौती है। पैठ का संकट पूरे राष्ट्रीय क्षेत्र पर प्रभावी प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित करने की समस्या है। अंततः, भागीदारी का संकट बढ़ती जन-मांगों और निर्णय लेने की प्रक्रिया में नए समूहों को शामिल करने की समस्या से संबंधित है। इन संकटों का समाधान ही राजनीतिक परिपक्वता का सूचक है।

170. (B) राज्यों की आंतरिक राजनीति।
तुलनात्मक राजनीति का प्राथमिक केंद्र विभिन्न देशों की आंतरिक राजनीतिक व्यवस्थाओं, संस्थानों और प्रक्रियाओं का अध्ययन करना है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध मुख्य रूप से संप्रभु राज्यों के बीच के बाहरी संबंधों और कूटनीति पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तुलनात्मक राजनीति यह विश्लेषण करती है कि किसी देश के भीतर सत्ता का वितरण कैसे होता है, सरकारें कैसे कार्य करती हैं और नागरिक राजनीति में कैसे भाग लेते हैं। यह विषय विभिन्न देशों की घरेलू परिस्थितियों की तुलना करके शासन के विविध पैटर्न को समझने और राजनीतिक सिद्धांतों को परिष्कृत करने का प्रयास करता है।

171. (B) अधिकारियों के बाध्यकारी निर्णय और कार्य।
डेविड ईस्टन के राजनीतिक व्यवस्था मॉडल में 'निर्गत' उन अंतिम परिणामों को संदर्भित करते हैं जो व्यवस्था रूपांतरण प्रक्रिया के बाद समाज को प्रदान करती है। इनमें आधिकारिक कानून, कार्यकारी निर्णय, नीतियां, कर और न्यायिक आदेश शामिल होते हैं। ये निर्गत समाज के लिए बाध्यकारी होते हैं और संसाधनों के वितरण को निर्धारित करते हैं। ये सीधे तौर पर पर्यावरण को प्रभावित करते हैं और फिर प्रतिपुष्टि के माध्यम से नई मांगों या समर्थन को जन्म देते हैं। अतः, निर्गत वह माध्यम है जिसके द्वारा सरकार अपनी शक्ति का प्रयोग करके सामाजिक समस्याओं का समाधान करती है।

172. (A) अधिकांश संसदीय प्रणालियाँ।
संसदीय शासन प्रणालियों की एक विशिष्ट पहचान राष्ट्राध्यक्ष और सरकार के प्रमुख की भूमिकाओं का स्पष्ट पृथक्करण है। यहाँ राष्ट्राध्यक्ष (जैसे भारत में राष्ट्रपति या यूनाइटेड किंगडम में सम्राट) मुख्य रूप से एक औपचारिक और प्रतीकात्मक पद होता है जो राज्य की एकता का प्रतिनिधित्व करता है। इसके विपरीत, सरकार का प्रमुख (प्रधानमंत्री) वास्तविक कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करता है और शासन का दैनिक संचालन करता है। यह व्यवस्था राष्ट्रपति प्रणाली से भिन्न है जहाँ ये दोनों भूमिकाएं एक ही व्यक्ति में निहित होती हैं।

173. (C) इसकी यह आशावादी मान्यता कि सभी परिवर्तन प्रगति हैं और स्थिरता की ओर ले जाते हैं।
'राजनीतिक पतन' की अवधारणा सैमुअल हंटिंगटन द्वारा प्रारंभिक आधुनिकीकरण सिद्धांत की उस आशावादी धारणा को चुनौती देने के लिए प्रस्तुत की गई थी जिसमें माना गया था कि विकास हमेशा स्थिरता और लोकतंत्र की ओर ले जाता है। हंटिंगटन ने तर्क दिया कि तीव्र सामाजिक और आर्थिक बदलाव अक्सर ऐसी मांगें पैदा करते हैं जिन्हें कमजोर राजनीतिक संस्थाएं सहन नहीं कर पातीं। इसके परिणामस्वरूप व्यवस्था में अव्यवस्था, हिंसा और शासन की विफलता हो सकती है। अतः, उन्होंने विकास को केवल प्रगति के रूप में देखने के बजाय संस्थागत क्षमता और स्थिरता के संदर्भ में देखने पर बल दिया।

NODIA

174. (B) परिवार
राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया में परिवार को सबसे प्रभावशाली अभिकर्ता माना जाता है क्योंकि यहीं से व्यक्ति के जीवन की आधारभूत शिक्षा प्रारंभ होती है। बचपन के ग्रहणशील वर्षों के दौरान, बच्चा अपने माता-पिता के राजनीतिक झुकाव, चर्चाओं और मूल्यों को अनजाने में आत्मसात कर लेता है। ये प्रारंभिक संस्कार इतने गहरे होते हैं कि वे व्यक्ति की दीर्घकालिक राजनीतिक पहचान और व्यवस्था के प्रति उसके नजरिए को आकार देते हैं। अन्य अभिकर्ता जैसे विद्यालय या मीडिया बाद में आते हैं, लेकिन परिवार द्वारा डाली गई नींव अक्सर जीवन भर स्थिर बनी रहती है।

175. (B) सभी संगठनों पर अनिवार्य रूप से एक छोटे अभिजन का प्रभुत्व हो जाता है।
रॉबर्ट मिचल्स द्वारा प्रतिपादित 'अल्पतंत्र का लौह नियम' यह तथ्य उजागर करता है कि प्रत्येक संगठन, चाहे उसकी विचारधारा कितनी भी लोकतांत्रिक क्यों न हो, अंततः एक छोटे से नेतृत्व समूह के नियंत्रण में आ जाता है। मिचल्स का तर्क था कि संगठन को चलाने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता, प्रशासनिक जटिलता और नेतृत्व की मनोवैज्ञानिक श्रेष्ठता सत्ता के केंद्रीकरण को अपरिहार्य बना देती है। सामान्य सदस्य धीरे-धीरे निष्क्रिय हो जाते हैं और वे केवल नेताओं के निर्णयों का अनुसरण करने तक सीमित रह जाते हैं, जो लोकतंत्र के आदर्श को चुनौती देता है।

176. (A) यह मानता है कि सभी प्रणालियों को जीवित रहने के लिए बुनियादी कार्य करने चाहिए।
संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण की एक प्रमुख विशेषता यह है कि यह राजनीतिक व्यवस्था को एक जीवित जीव की तरह देखता है जिसे अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कुछ अनिवार्य प्रकार्य पूरे करने होते हैं। यह दृष्टिकोण उन विभिन्न संरचनाओं का अध्ययन करता है जो इन कार्यों को संपन्न करती हैं। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह विविध संस्कृतियों और विभिन्न विकास स्तरों वाली प्रणालियों के बीच तुलना के लिए एक तटस्थ और वैज्ञानिक ढांचा प्रदान करता है, जो केवल औपचारिक-कानूनी संस्थानों तक सीमित नहीं रहता।

177. (B) सीमित दायरा रखा, जो मुख्य रूप से पश्चिमी संस्थानों का अध्ययन करता था।
तुलनात्मक राजनीति के पारंपरिक दृष्टिकोण की 'संकीर्ण' होने के लिए आलोचना इसलिए की गई क्योंकि यह लगभग पूरी तरह से पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका की सरकारों तक सीमित था। इसने एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की उभरती और विविध राजनीतिक प्रणालियों की लंबे समय तक उपेक्षा की। इसके अतिरिक्त, इसका केंद्र केवल लिखित संविधानों और औपचारिक संस्थानों के कानूनी विवरण पर था, जिसके कारण इसने गैर-पश्चिमी समाजों में प्रभावी रहने वाली अनौपचारिक प्रक्रियाओं, सांस्कृतिक कारकों और वास्तविक राजनीतिक व्यवहार को पूरी तरह अनदेखा कर दिया।

178. (B) दो पृथक कक्षों या सदनों से बनी एक विधायिका।
'द्विसदनीयता' उस विधायी संरचना को संदर्भित करती है जिसमें कानून बनाने वाला निकाय दो अलग-अलग सदनों या कक्षों में विभाजित होता है। सामान्यतः, एक सदन सीधे जनता का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि दूसरा सदन राज्यों, क्षेत्रों या विशिष्ट समूहों के हितों की रक्षा करता है। यह व्यवस्था शक्तियों के संतुलन को सुदृढ़ करने, जल्दबाजी में किए गए विधायी निर्णयों पर रोक लगाने और राष्ट्रीय राजनीति में विभिन्न दृष्टिकोणों को शामिल करने में सहायक होती है। यह विशेष रूप से संघीय शासन प्रणालियों में एक अनिवार्य विशेषता मानी जाती है।

179. (C) उसे प्रभावित करने का प्रयास किए बिना चुपचाप सरकार की आज्ञा का पालन करते हैं।
गैब्रियल आलमंड और सिडनी वर्बा के अनुसार, 'प्रजाभावी' राजनीतिक संस्कृति वह है जहाँ नागरिक सरकार की नीतियों और कानूनों के प्रति जागरूक तो होते हैं, लेकिन वे स्वयं को व्यवस्था का एक निष्क्रिय हिस्सा मानते हैं। ऐसे समाज में लोगों का ध्यान मुख्य रूप से सरकार के निर्गत कार्यों, जैसे नियमों के पालन और सरकारी लाभों की प्राप्ति पर होता है। उनमें यह विश्वास या प्रेरणा नहीं होती कि वे अपनी सक्रिय भागीदारी के माध्यम से शासन को प्रभावित या बदल सकते हैं, जिससे राजनीतिक प्रक्रिया में उनकी भूमिका केवल आज्ञाकारी प्रजा तक सीमित रह जाती है।

180. (C) अभिजनवादी या प्रक्रियात्मक
जोसेफ शुम्पेटर ने लोकतंत्र के 'अभिजनवादी' या 'प्रक्रियात्मक' सिद्धांत का समर्थन किया, जिसने लोकतंत्र की पारंपरिक परिभाषा को बदल दिया। उनके अनुसार, लोकतंत्र वह व्यवस्था नहीं है जहाँ जनता वास्तव में शासन करती है, बल्कि यह वह विधि है जिसके माध्यम से जनता प्रतिस्पर्धी नेताओं या अभिजनों के बीच चुनाव करती है जो उन पर शासन करेंगे। शुम्पेटर ने लोकतंत्र को एक बाजार की तरह देखा जहाँ राजनीतिक दल मतों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। यहाँ नागरिकों की प्राथमिक भूमिका केवल अपने शासकों को वैधता प्रदान करने के लिए मतदान करने तक ही सीमित मानी गई है।

181. (B) जनता की मांगों और समर्थनों का नीतियों में परिवर्तन।
डेविड ईस्टन के व्यवस्था दृष्टिकोण में 'रूपांतरण प्रक्रिया' वह केंद्रीय तंत्र है जहाँ राजनीतिक व्यवस्था समाज से प्राप्त आगत को संसाधित करती है। इस प्रक्रिया में सरकार के विभिन्न अंग, जैसे विधायिका और कार्यपालिका, इन मांगों को तौलते हैं, प्राथमिकताएं निर्धारित करते हैं और अंततः उन्हें आधिकारिक नीतियों, कानूनों या निर्णयों के रूप में 'निर्गत' में बदल देते हैं। यह प्रक्रिया राजनीतिक व्यवस्था की कार्यक्षमता और समाज के प्रति उसकी संवेदनशीलता को दर्शाती है, जो व्यवस्था की निरंतरता और सामाजिक संतुलन बनाए रखने के लिए अनिवार्य है।

182. (A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं और कथन II, कथन I की सही व्याख्या है।
राष्ट्रपति प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती और न ही उसे अविश्वास प्रस्ताव से हटाया जा सकता है। इस स्वायत्तता के कारण शक्ति के दुरुपयोग का खतरा रहता है, जिसे रोकने के लिए एक लिखित संविधान और न्यायिक समीक्षा अत्यंत आवश्यक हो जाते हैं। लिखित संविधान शक्तियों का स्पष्ट सीमांकन करता है, जबकि न्यायपालिका यह सुनिश्चित करती है कि राष्ट्रपति अपनी संवैधानिक सीमाओं का उल्लंघन न करे। अतः, संसदीय जवाबदेही की अनुपस्थिति में कानूनी और संवैधानिक नियंत्रण ही शासन को मर्यादित और लोकतांत्रिक बनाए रखने का एकमात्र प्रभावी जरिया होते हैं।

NODIA

183. (B) अभिजन सिद्धांत
अभिजन सिद्धांत का मुख्य केंद्र यह अध्ययन करना है कि समाज में सत्ता का केंद्रीकरण कैसे होता है और सत्तारूढ़ समूहों की उत्पत्ति तथा उनका संचलन कैसे होता है। यह सिद्धांत मानता है कि अल्पसंख्यक अभिजन अपनी संगठनात्मक क्षमता और संसाधनों के कारण हमेशा बहुसंख्यक जनता पर शासन करते हैं। विल्फ्रेडो पेरेटो और गेटानो मोस्का जैसे विद्वानों ने विश्लेषण किया कि कैसे एक अभिजन वर्ग दूसरे का स्थान लेता है और शासन की निरंतरता बनी रहती है। यह दृष्टिकोण लोकतंत्र की उस धारणा को चुनौती देता है जिसमें शक्ति जनता के पास मानी जाती है।

184. (A) अनुसंधान सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए प्रासंगिक होना चाहिए।
उत्तर-व्यवहारवाद 1960 के दशक के अंत में उभरा, जिसने व्यवहारवाद की 'तकनीकी शुद्धता' और 'मूल्य-तटस्थता' की कड़ी आलोचना की। इसके समर्थकों ने तर्क दिया कि राजनीति विज्ञान को केवल डेटा और आंकड़ों के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि उसे समाज की ज्वलंत समस्याओं जैसे युद्ध, गरीबी और अन्याय के प्रति 'प्रासंगिक' होना चाहिए। उन्होंने 'कार्रवाई' पर बल देते हुए कहा कि विद्वानों का उत्तरदायित्व केवल सिद्धांत बनाना नहीं, बल्कि मानवीय मूल्यों की रक्षा करना और समाज में सुधार लाने के लिए सक्रिय भूमिका निभाना भी है।

185. (B) केवल 2 और 3
राजनीतिक संचार केवल सरकार से जनता तक सूचना का एकतरफा प्रवाह नहीं है, बल्कि यह एक द्विमार्गी प्रक्रिया है जिसमें जनता की प्रतिक्रियाएं भी सरकार तक पहुँचती हैं। आधुनिक समय में, जनसंचार माध्यम इस प्रक्रिया के सबसे प्रमुख संस्थान हैं जो सूचनाओं को संसाधित और प्रसारित करते हैं। यह संचार न केवल नागरिकों के राजनीतिक समाजीकरण में मदद करता है, बल्कि यह हित प्रकटीकरण के एक माध्यम के रूप में भी कार्य करता है। प्रभावी संचार व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था की पारदर्शिता और जवाबदेही को सुदृढ़ बनाती है।

186. (A) एक संसदीय संवैधानिक राजतंत्र
यूनाइटेड किंगडम की राजनीतिक व्यवस्था को 'संसदीय संवैधानिक राजतंत्र' के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यहाँ राष्ट्राध्यक्ष एक सम्राट होता है जिसका पद वंशानुगत और मुख्य रूप से औपचारिक होता है। वास्तविक कार्यकारी शक्तियां प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल के पास होती हैं, जो संसद से लिया जाता है और उसके प्रति उत्तरदायी होता है। यह व्यवस्था लोकतंत्र और परंपरा का एक अनूठा संगम है, जहाँ संविधान लिखित रूप में नहीं है, लेकिन संप्रभुता संसद में निहित है और शासन कानूनी रीति-रिवाजों और परंपराओं पर आधारित है।

187. (B) उत्पादन की विधि
मार्क्सवादी अवधारणा के अनुसार, 'उत्पादन की विधि' समाज के 'आधार' का हिस्सा है, न कि अधिसंरचना का। आधार में उत्पादक शक्तियाँ और उत्पादन के संबंध शामिल होते हैं, जो समाज की आर्थिक नींव बनाते हैं। इसके विपरीत, 'अधिसंरचना' में कानूनी प्रणाली, राजनीतिक संस्थान, शिक्षा, धर्म और प्रभावी विचारधारा शामिल होती है जो इस आर्थिक आधार पर टिकी होती है और उसे सुदृढ़ करती है। मार्क्स का मानना था कि आर्थिक आधार ही यह निर्धारित करता है कि अधिसंरचना की प्रकृति कैसी होगी, जो अंततः शासक वर्ग के हितों की सेवा करती है।

188. (D) तीव्र परिवर्तन के सम्मुख राजनीतिक संस्थाओं का चरमराना।
'राजनीतिक पतन' शब्द का प्रयोग सैमुअल हंटिंगटन ने उस स्थिति को वर्णित करने के लिए किया जहाँ किसी समाज में राजनीतिक संस्थाएं अपनी प्रभावशीलता और व्यवस्था बनाए रखने की क्षमता खो देती हैं। यह अक्सर तब होता है जब तीव्र आधुनिकीकरण के कारण सामाजिक गतिशीलता और राजनीतिक भागीदारी इतनी बढ़ जाती है कि विद्यमान संस्थाएं उन्हें आत्मसात नहीं कर पातीं। इसके परिणामस्वरूप भ्रष्टाचार, अस्थिरता और हिंसा बढ़ती है। अतः, पतन का अर्थ केवल संस्थाओं का पुराना होना नहीं, बल्कि बदलती सामाजिक मांगों के साथ तालमेल बिठाने में उनकी विफलता है।

189. (B) राजनीतिक दल
संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक ढांचे में 'हित समूहन' का कार्य मुख्य रूप से राजनीतिक दलों द्वारा संपन्न किया जाता है। हित समूहन वह प्रक्रिया है जिसमें समाज के विभिन्न समूहों द्वारा की गई अनेक और कभी-कभी विरोधाभासी मांगों को एकीकृत करके कुछ स्पष्ट नीतिगत विकल्पों या चुनावी कार्यक्रमों में बदला जाता है। राजनीतिक दल विभिन्न दबाव समूहों और जनता के बीच तालमेल बिठाते हैं, जिससे शासन के लिए एक स्पष्ट और प्रबंधनीय कार्यसूची तैयार होती है। यह कार्य राजनीतिक व्यवस्था की कार्यक्षमता बढ़ाने और अराजकता को रोकने के लिए अत्यंत आवश्यक माना जाता है।

190. (B) सत्तारूढ़ अभिजन को चुनने के लिए एक शांतिपूर्ण साधन प्रदान करना।
अभिजनवादी सिद्धांत के अनुसार, चुनावों का प्राथमिक उद्देश्य जनता को वास्तविक शासन शक्ति देना नहीं है, क्योंकि वे मानते हैं कि शासन हमेशा अल्पसंख्यक अभिजन ही करेंगे। इसके बजाय, चुनाव अभिजनों के बीच सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा का एक औपचारिक और शांतिपूर्ण माध्यम प्रदान करते हैं। यह प्रक्रिया जनता को यह महसूस कराती है कि शासन में उनकी भागीदारी है, जिससे नई सरकार को वैधता प्राप्त होती है। इस प्रकार, चुनाव सत्ता के हस्तांतरण को विनियमित करते हैं और व्यवस्था की स्थिरता सुनिश्चित करते हैं।

191. (A) विधायिका सामान्य नियम बनाती है, जबकि न्यायपालिका उन्हें विशिष्ट मामलों पर लागू करती है।
विधायी और न्यायिक अंगों के बीच कार्यात्मक अंतर शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का मूल है। विधायिका का मुख्य कार्य पूरे समाज के लिए सामान्य कानूनों और भविष्योन्मुखी नियमों का निर्माण करना है। इसके विपरीत, न्यायपालिका का उत्तरदायित्व उन सामान्य कानूनों की व्याख्या करना और उन्हें विशिष्ट कानूनी विवादों या व्यक्तिगत मामलों पर लागू करके न्याय प्रदान करना है। विधायिका नीतिगत दिशा निर्धारित करती है, जबकि न्यायपालिका यह सुनिश्चित करती है कि उन नीतियों और कानूनों का क्रियान्वयन संवैधानिक सीमाओं के भीतर हो, जिससे कानून का शासन बना रहे।

192. (B) व्यवस्था दृष्टिकोण
'आगत', 'निर्गत', 'प्रतिपुष्टि' और 'पर्यावरण' जैसे शब्द डेविड ईस्टन द्वारा प्रतिपादित 'व्यवस्था दृष्टिकोण' के आधारभूत अंग हैं। यह दृष्टिकोण राजनीति को एक परस्पर निर्भर और गतिशील प्रक्रिया के रूप में देखता है जहाँ राजनीतिक व्यवस्था पर्यावरण से मांगें और समर्थन प्राप्त करती है और उन्हें आधिकारिक निर्णयों में बदलती है। प्रतिपुष्टि तंत्र यह सुनिश्चित करता है कि निर्णयों

Downloaded from www.pdf.tube

का प्रभाव वापस आगत के रूप में व्यवस्था तक पहुँचे। यह समग्र ढांचा राजनीतिक व्यवस्था की स्थिरता, अनुकूलन और निरंतरता को वैज्ञानिक रूप से समझने के लिए एक व्यापक उपकरण प्रदान करता है।

193. (B) राजनीतिक वस्तुओं के प्रति मनोवैज्ञानिक अभिवृत्ति के स्वरूप।
राजनीतिक संस्कृति का तुलनात्मक अध्ययन किसी समाज के औपचारिक कानूनों के बजाय नागरिकों के मन में राजनीति के प्रति मौजूद व्यक्तिपरक भावनाओं, विश्वासों और मूल्यों के विश्लेषण पर केंद्रित होता है। इसमें यह जांचा जाता है कि लोग अपनी राजनीतिक व्यवस्था, संस्थाओं और नेताओं को किस नजरिए से देखते हैं। विद्वान यह समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे ये मनोवैज्ञानिक स्वरूप—जैसे विश्वास, गौरव या उदासीनता—विभिन्न देशों में राजनीतिक स्थिरता और लोकतांत्रिक सफलता को प्रभावित करते हैं। यह दृष्टिकोण राजनीति के अध्ययन में एक अत्यंत महत्वपूर्ण आयाम जोड़ता है।

194. (A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।
तुलनात्मक राजनीति एक विषय के रूप में निरंतर विकास की प्रक्रिया में है। आधुनिक काल में यह अनुशासन अपनी पद्धतिगत कठोरता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लिए जाना जाता है, जहाँ शोध में सांख्यिकीय विधियों और डेटा का व्यापक प्रयोग होता है। इसका प्राथमिक लक्ष्य केवल अलग-अलग देशों का वर्णन करना नहीं है, बल्कि विभिन्न देशों के बीच मौजूद राजनीतिक पैटर्न, समानताओं और विविधताओं की पहचान करके उनके कारणों को समझाना है। यह दृष्टिकोण इसे एक अधिक विश्वसनीय और सिद्धांत-उन्मुख विज्ञान बनाता है।

195. (B) बल; अनुनय और चतुराई
विल्फ्रेडो पेरेटो के अभिजन सिद्धांत में, 'शेर' और 'लोमड़ी' शासन करने की दो विपरीत शैलियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 'शेर' वे अभिजन हैं जो मुख्य रूप से सीधे बल प्रयोग, अनुशासन और दृढ़ता के माध्यम से सत्ता बनाए रखते हैं; वे अक्सर रूढ़िवादी और स्थिर व्यवस्था के समर्थक होते हैं। इसके विपरीत, 'लोमड़ी' वे नेता हैं जो अनुनय, चतुराई, कूटनीति, हेरफेर और वित्तीय सौदेबाजी के माध्यम से शासन करते हैं। पेरेटो का मानना था कि समाज में शक्ति का निरंतर प्रवाह इन दो प्रकार के अभिजनों के बीच होता रहता है।

196. (A) P-3, Q-1, R-2, S-4
विभिन्न शासन प्रणालियाँ अपनी संवैधानिक संरचना और शक्ति के वितरण में भिन्न होती हैं। राष्ट्रपति प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका के बीच शक्तियों का सख्त पृथक्करण होता है। संसदीय प्रणाली की पहचान इन दोनों अंगों के बीच शक्तियों के संलयन और आपसी उत्तरदायित्व से है। अर्ध-राष्ट्रपति प्रणाली में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच 'दोहरी कार्यपालिका' की व्यवस्था होती है। एकात्मक प्रणालियों में शक्ति का पूर्ण केंद्रीकरण केंद्र सरकार में होता है, जहाँ उप-इकाइयों की स्वायत्तता सीमित होती है।

197. (C) पारंपरिक से तर्कसंगत-कानूनी सत्ता की ओर।
मैक्स वेबर के विचारों के अनुसार, राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में सत्ता की वैधता का आधार बदल जाता है। पारंपरिक समाजों में, शासन का अधिकार पुराने रीति-रिवाजों, वंशानुगत उत्तराधिकार या परंपराओं पर आधारित होता है। आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था में यह वैधता 'तर्कसंगत-कानूनी' सत्ता की ओर स्थानांतरित हो जाती है, जहाँ शासन का अधिकार संवैधानिक नियमों, निष्पक्ष चुनावों और लिखित कानूनों से प्राप्त होता है। यह बदलाव शासन में अधिक पारदर्शिता, दक्षता और व्यावसायिकता लाता है, जो संस्थागत विकास की एक अनिवार्य पहचान है।

198. (B) राजनीतिक समाजीकरण
राजनीतिक समाजीकरण वह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसके माध्यम से नागरिक अपने राजनीतिक विश्वासों, मूल्यों और अभिवृत्तियों को सीखते हैं। परिवार प्रारंभिक वर्षों में आधारभूत मूल्यों का निर्माण करता है, जबकि विद्यालय औपचारिक शिक्षा और नागरिक गौरव की भावना प्रदान करते हैं। जनसंचार माध्यम वर्तमान घटनाओं और सूचनाओं के माध्यम से नागरिकों की धारणाओं को आकार देते हैं। यह अध्ययन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह स्पष्ट करता है कि कैसे एक समाज अपनी राजनीतिक संस्कृति को अगली पीढ़ी तक पहुँचाता है और व्यवस्था के प्रति समर्थन या विरोध की भावनाएं कैसे विकसित होती हैं।

199. (A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं और कथन II, कथन I की सही व्याख्या है।
राजनीति विज्ञान के अंतर्गत तुलनात्मक राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंध दो अलग-अलग क्षेत्र हैं। तुलनात्मक राजनीति का मुख्य ध्यान विभिन्न राष्ट्रों के 'भीतर' की राजनीतिक प्रणालियों, घरेलू संस्थानों, प्रक्रियाओं और व्यवहारों की तुलना करने पर होता है। इसके विपरीत, अंतर्राष्ट्रीय संबंध मुख्य रूप से संप्रभु राज्यों के बीच के 'बाहरी' संबंधों, कूटनीति, युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर केंद्रित होते हैं। अतः, तुलनात्मक राजनीति घरेलू राजनीति के आंतरिक कामकाज को समझने का प्रयास करती है, जो इसे अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र की राजनीति से अलग और विशिष्ट बनाती है।

200. (A) किसी भी बड़े संगठन में नेतृत्व एक स्वयं को बनाए रखने वाला अल्पतंत्र बन जाता है।
रॉबर्ट मिचल्स द्वारा प्रतिपादित 'अल्पतंत्र का लौह नियम' यह तर्क देता है कि जैसे-जैसे कोई संगठन बड़ा और जटिल होता है, उसमें सत्ता का केंद्रीकरण अनिवार्य हो जाता है। संगठन चलाने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता और प्रशासनिक कुशलता के कारण एक छोटा सा नेतृत्व समूह स्थायी हो जाता है, जो संगठन के संसाधनों और सूचनाओं पर नियंत्रण कर लेता है। यह समूह धीरे-धीरे सामान्य सदस्यों से कट जाता है और अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए ही कार्य करने लगता है, जिससे संगठन का मूल लोकतांत्रिक स्वरूप समाप्त हो जाता है।

201. (C) व्यवस्था के आधिकारिक निर्णय और नीतियां।
डेविड ईस्टन के राजनीतिक व्यवस्था मॉडल में 'निर्गत' उन ठोस परिणामों को दर्शाते हैं जो व्यवस्था द्वारा आगत को

NODIA

234. (B) समाज के लिए मूल्यों का आधिकारिक रूप से आवंटन किया जाता है।
डेविड ईस्टन के प्रणालीगत मॉडल के अनुसार, 'राजनीतिक व्यवस्था' उन अंतःक्रियाओं का एक जटिल जाल है जिसके माध्यम से समाज के लिए 'मूल्यों का आधिकारिक आवंटन' किया जाता है। यहाँ 'मूल्य' का अर्थ समाज के वे दुर्लभ संसाधन और अधिकार हैं जिनकी सभी को आवश्यकता होती है। 'आधिकारिक' का तात्पर्य है कि व्यवस्था द्वारा लिए गए निर्णय पूरे समाज के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी होते हैं। यह दृष्टिकोण राजनीति को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में देखता है जहाँ सत्ता का उपयोग समाज की प्राथमिकताओं को निर्धारित करने और संघर्षों का समाधान करने के लिए किया जाता है।

235. (A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।
आधुनिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में विधायिका और न्यायपालिका के कार्यों का स्पष्ट विभाजन शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का आधार है। विधायिका का प्राथमिक उत्तरदायित्व जनमत और राष्ट्र की आवश्यकताओं के अनुरूप नए कानूनों और नियमों का निर्माण करना है। इसके साथ ही, न्यायपालिका का मुख्य कार्य उन कानूनों की व्याख्या करना और यह सुनिश्चित करना है कि उनका अनुप्रयोग विशिष्ट मामलों और संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार निष्पक्ष रूप से हो। इन दोनों अंगों का अपने-अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र और प्रभावी रूप से कार्य करना ही कानून के शासन और नागरिक स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए अनिवार्य है।

236. (C) एक सहभागी संस्कृति
'सहभागी' राजनीतिक संस्कृति उस समाज की विशेषता है जहाँ नागरिक राजनीतिक व्यवस्था के प्रति अत्यधिक जागरूक होते हैं और स्वयं को उसका सक्रिय हिस्सा मानते हैं। ऐसे समाज में लोगों को यह विश्वास होता है कि वे अपनी सक्रियता, मतदान और विरोध के माध्यम से सरकारी निर्णयों को प्रभावी ढंग से प्रभावित कर सकते हैं। उनमें उच्च राजनीतिक प्रभावकारिता होती है और वे शासन की आगत और निर्गत दोनों प्रक्रियाओं में गहरी रुचि लेते हैं। यह संस्कृति लोकतंत्र की सफलता और उसकी दीर्घकालिक स्थिरता के लिए सबसे उपयुक्त और अनिवार्य मनोवैज्ञानिक आधार मानी जाती है।

237. (C) प्रभावी आर्थिक वर्ग
मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार, राज्य समाज के सामान्य हितों की सेवा करने वाला कोई तटस्थ निकाय नहीं है, बल्कि यह उस आर्थिक वर्ग का एक साधन है जिसका उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण होता है। पूंजीवादी व्यवस्था में, राज्य बुर्जुआ वर्ग के हितों की रक्षा करता है और सर्वहारा वर्ग के दमन और शोषण को वैध बनाता है। मार्क्सवाद का मानना है कि कानून, पुलिस और सेना सभी इसी प्रभावी वर्ग के प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए कार्य करते हैं। अतः, राजनीति अंततः वर्ग संघर्ष का ही एक रूप है जहाँ राज्य सत्ता का उपयोग वर्ग हितों को साधने के लिए किया जाता है।

238. (D) 1, 2 और 3
सी. राइट मिल्स ने 1950 के दशक के अमेरिका का सूक्ष्म विश्लेषण करते हुए तर्क दिया कि वहाँ एक एकीकृत 'शक्ति अभिजन' का अस्तित्व है जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निर्णय लेता है। मिल्स के अनुसार, यह अभिजन तीन क्षेत्रों—कॉर्पोरेट जगत, सैन्य नेतृत्व और शीर्ष राजनीतिक पदों—के नेताओं के बीच गहरे तालमेल और सामाजिक संबंधों से बना है। यह समूह अपनी संस्थागत शक्ति के कारण जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होता और वह लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बाहर रहकर शासन को नियंत्रित करता है। यह विचार लोकतंत्र की उस लोकप्रिय धारणा को चुनौती देता है जिसमें शक्ति जनता के पास मानी जाती है।

239. (C) विभिन्न देशों में समानताओं और अंतरों की पहचान करना और उनकी व्याख्या करना।
राजनीति विज्ञान में 'तुलनात्मक पद्धति' एक अत्यंत महत्वपूर्ण शोध उपकरण है जिसका मुख्य लक्ष्य विभिन्न देशों की राजनीतिक प्रणालियों, व्यवहारों और संस्थानों का व्यवस्थित अध्ययन करना है। यह पद्धति केवल विवरण देने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समानताओं और विविधताओं के पीछे के कारणों की वैज्ञानिक व्याख्या करने का प्रयास करती है। तुलना के माध्यम से विद्वान ऐसे सामान्य सिद्धांतों और परिकल्पनाओं का निर्माण करते हैं जिनका परीक्षण वैश्विक स्तर पर किया जा सके। यह पद्धति राजनीति विज्ञान को एक वास्तविक विश्लेषणात्मक और वैज्ञानिक अनुशासन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

240. (C) व्यक्ति अपने राजनीतिक मूल्यों, विश्वासों और अभिवृत्तियों को कैसे प्राप्त करते हैं।
राजनीतिक समाजीकरण की अवधारणा उस सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया से संबंधित है जिसके माध्यम से व्यक्ति बचपन से ही राजनीति के प्रति अपने विचारों, मूल्यों और झुकाव को ग्रहण करता है। यह प्रक्रिया आजीवन चलती रहती है और व्यक्ति को उसकी राजनीतिक व्यवस्था के अनुरूप ढालती है। इसके माध्यम से ही समाज की राजनीतिक संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक प्रेषित होती है। परिवार, विद्यालय, कार्यस्थल और मीडिया इस प्रक्रिया के मुख्य वाहक हैं जो व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार और नागरिक पहचान को आकार देते हैं, जिससे व्यवस्था को जन समर्थन और निरंतरता प्राप्त होती है।

241. (C) न्यायपालिका
सरकार का न्यायिक अंग 'नियम अधिनिर्णयन' के लिए संवैधानिक रूप से उत्तरदायी है। इसका अर्थ है विशिष्ट विवादों में कानूनों की व्याख्या करना, यह तय करना कि कानून का उल्लंघन हुआ है या नहीं, और दोषी को दंड देना। न्यायपालिका यह सुनिश्चित करती है कि शासन संविधान और कानून के अनुसार चले। यह कार्य विधायिका और कार्यपालिका से स्वतंत्र होकर किया जाना चाहिए ताकि निष्पक्षता बनी रहे। किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में न्यायपालिका का यह कार्य

Click Here to Buy book on Amazon

प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। अतः, राज्यों के आपसी संवाद इसके प्रत्यक्ष और प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा नहीं माने जाते हैं।

210. (D) 1, 2 और 3
राजनीतिक अभिजनों के अध्ययन ने समाज में शक्ति के वितरण को समझने के लिए महत्वपूर्ण आयाम दिए हैं। शास्त्रीय सिद्धांतकारों ने यह तर्क दिया कि एक संगठित अल्पसंख्यक का शासन अपरिहार्य है। सी. राइट मिल्स ने 20वीं सदी के अमेरिका में एक एकीकृत 'शक्ति अभिजन' की पहचान की जो कॉर्पोरेट, सैन्य और राजनीति के शीर्ष पर था। जोसेफ शुम्पेटर ने लोकतंत्र को प्रतिस्पर्धी अभिजनवाद के रूप में परिभाषित किया, जहाँ जनता अभिजनों के बीच चुनाव करती है। ये तीनों विचार सामूहिक रूप से आधुनिक समाज में नेतृत्व और सत्ता की प्रकृति को स्पष्ट करते हैं।

211. (B) सरकारी कार्रवाई के बारे में जानकारी वापस व्यवस्था में भेजी जाती है।
डेविड ईस्टन के व्यवस्था विश्लेषण में प्रतिपुष्टि (फीडबैक) एक अनिवार्य प्रक्रिया है जो राजनीतिक व्यवस्था की निरंतरता को सुनिश्चित करती है। जब सरकार कोई निर्णय लेती है या नीति लागू करती है, तो समाज और पर्यावरण पर उसके प्रभावों की जानकारी वापस आगत के रूप में व्यवस्था तक पहुँचती है। यह जानकारी व्यवस्था को यह समझने में मदद करती है कि उसकी नीतियां कितनी सफल रहीं और जनता की नई मांगें क्या हैं। प्रतिपुष्टि के बिना, व्यवस्था पर्यावरण से कट जाएगी और अपनी अनुकूलन क्षमता खो देगी, जिससे उसका अस्तित्व संकट में पड़ सकता है।

212. (A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।
संसदीय संप्रभुता और न्यायिक समीक्षा के बीच का अंतर विभिन्न लोकतांत्रिक प्रणालियों की कार्यशैली को स्पष्ट करता है। यूनाइटेड किंगडम में 'संसदीय संप्रभुता' का सिद्धांत है, जिसका अर्थ है कि संसद द्वारा बनाया गया कानून सर्वोच्च है और न्यायालय उसे असंवैधानिक घोषित करके रद्द नहीं कर सकते। इसके विपरीत, संयुक्त राज्य अमेरिका में 'न्यायिक समीक्षा' की शक्ति अत्यंत सुदृढ़ है, जहाँ उच्चतम न्यायालय किसी भी कानून या कार्यकारी कार्य की संवैधानिकता की जाँच कर उसे शून्य घोषित कर सकता है। ये दोनों व्यवस्थाएं दर्शाती हैं कि कैसे अलग-अलग देशों ने सत्ता के संतुलन को लागू किया है।

213. (B) प्राथमिक चुनौती प्रभावी संस्थानों के निर्माण से जुड़ी है।
राजनीतिक विकास सिद्धांत का एक केंद्रीय तर्क, विशेष रूप से सैमुअल हंटिंगटन जैसे विद्वानों के अनुसार, यह है कि विकास की मुख्य चुनौती मजबूत और प्रभावी राजनीतिक संस्थानों का निर्माण करना है। केवल आर्थिक वृद्धि या बढ़ती जनभागीदारी स्थिरता की गारंटी नहीं देती है। यदि संस्थान सामाजिक मांगों और तनावों को झेलने के लिए पर्याप्त रूप से 'संस्थाकृत' नहीं होते हैं, तो अव्यवस्था और पतन की संभावना बढ़ जाती है। अतः, सफल राजनीतिक विकास के लिए संस्थागत क्षमता का विस्तार करना और उन्हें अधिक प्रभावी बनाना ही प्राथमिक लक्ष्य माना जाता है।

214. (A) राजनीतिक संचार
राजनीतिक संचार वह प्रक्रिया है जिसमें सूचनाओं, विचारधाराएं और संदेशों का आदान-प्रदान राजनीतिक व्यवस्था और समाज के बीच होता है। जनसंचार माध्यम इसमें एक शक्तिशाली भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वे 'कार्यसूची-निर्धारण' के माध्यम से यह तय करते हैं कि किन मुद्दों को जनता के सामने प्रमुखता से रखा जाएगा। जब मीडिया किसी विषय को बार-बार उठाता है, तो जनता उसे महत्वपूर्ण समझने लगती है, जिससे सार्वजनिक प्राथमिकताओं का निर्माण होता है। यह प्रक्रिया लोकमत को आकार देने और सरकार को जन-चिंताओं के प्रति प्रतिक्रिया देने के लिए अनिवार्य उपकरण है।

215. (B) एक सत्तारूढ़ अभिजन का दूसरे द्वारा प्रतिस्थापन।
विल्फ्रेडो पेरेटो द्वारा प्रतिपादित 'अभिजनों का संचलन' की अवधारणा यह स्पष्ट करती है कि समाज में सत्ता का प्रवाह स्थिर नहीं होता है। उनका तर्क था कि समय के साथ सत्तारूढ़ अभिजन अपनी योग्यता या ऊर्जा खो देते हैं और फिर समाज के निचले स्तरों से उभरने वाला एक नया, अधिक सक्षम और ऊर्जावान समूह सत्ता पर कब्जा कर लेता है। पेरेटो ने इसे 'इतिहास अभिजनों का कब्रिस्तान है' कहकर वर्णित किया। यह प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि समाज में नेतृत्व का नवीनीकरण होता रहे, चाहे शासन का स्वरूप कोई भी क्यों न हो।

216. (B) कार्यकारी शाखा की निगरानी और पर्यवेक्षण।
विधायिका का 'निगरानी' कार्य आधुनिक लोकतंत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है कि संसद या विधानमंडल यह सुनिश्चित करता है कि कार्यपालिका अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न करे और कानून तथा बजट के प्रावधानों के अनुसार ही शासन चलाए। इसमें संसदीय समितियों, प्रश्नों, बहसों और अविश्वास प्रस्ताव जैसे माध्यमों का उपयोग किया जाता है। निगरानी का मुख्य उद्देश्य कार्यपालिका को जवाबदेह बनाना, भ्रष्टाचार को रोकना और यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी नीतियां जनहित में प्रभावी ढंग से लागू की जा रही हैं, जो शक्तियों के संतुलन का आधार है।

217. (B) जिस प्रकार वर्ग संरचनाएं राजनीतिक प्रणालियों को आकार देती हैं।
तुलनात्मक राजनीति में मार्क्सवादी दृष्टिकोण विश्लेषण के केंद्र में 'वर्ग' और 'आर्थिक आधार' को रखता है। यह दृष्टिकोण तर्क देता है कि राजनीति केवल स्वतंत्र व्यक्तियों की क्रिया नहीं है, बल्कि यह आर्थिक रूप से प्रभावी और शोषित वर्गों के बीच के संघर्ष का प्रतिबिंब है। मार्क्सवाद के अनुसार, राज्य की संस्थाएं, कानून और विचारधारा बुर्जुआ वर्ग के प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए निर्मित होती हैं। अतः, किसी भी राजनीतिक व्यवस्था को समझने के लिए उसके आर्थिक ढांचे और उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण रखने वाले वर्ग के हितों की जांच करना अनिवार्य है।

NODIA

संसाधित करने के बाद समाज के लिए जारी किए जाते हैं। इनमें विधायिका द्वारा पारित कानून, कार्यपालिका के निर्णय, नई सरकारी नीतियां, करों का निर्धारण और न्यायिक आदेश शामिल होते हैं। ये निर्णय समाज के लिए अनिवार्य होते हैं और वे संसाधनों के आधिकारिक आवंटन का प्रतिनिधित्व करते हैं। निर्गत का मुख्य कार्य सामाजिक समस्याओं का समाधान करना और व्यवस्था के प्रति समर्थन बनाए रखना है।

202. (D) आनुभविक डेटा और सांख्यिकीय विश्लेषण पर जोर
तुलनात्मक राजनीति के पारंपरिक दृष्टिकोण की मुख्य विशेषताओं में आदर्शात्मक पूर्वाग्रह, औपचारिक-कानूनी संस्थाओं पर ध्यान और वर्णनात्मक प्रकृति शामिल है। यह दृष्टिकोण 'क्या होना चाहिए' पर अधिक केंद्रित था और दार्शनिक तर्क प्रदान करता था। आनुभविक डेटा, सांख्यिकीय विश्लेषण और वैज्ञानिक विधियों पर जोर देना आधुनिक 'व्यवहारवादी' दृष्टिकोण की पहचान है, न कि पारंपरिक दृष्टिकोण की। पारंपरिक विद्वानों ने राजनीतिक प्रक्रियाओं के वास्तविक व्यवहार और मात्रात्मक मापन की उपेक्षा की थी, जिसके कारण इसे बाद में अधिक वैज्ञानिक दृष्टिकोणों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

203. (C) कार्यान्वयन
सरकार के कार्यकारी अंग की सबसे महत्वपूर्ण और प्राथमिक भूमिका विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों और नीतियों का समाज में प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन या निष्पादन करना है। कार्यपालिका शासन का वह हिस्सा है जो प्रशासनिक मशीनरी का संचालन करती है, सार्वजनिक सेवाओं का प्रबंधन करती है और कानून व्यवस्था सुनिश्चित करती है। इसमें राष्ट्राध्यक्ष और सरकार के प्रमुख से लेकर पूरी नौकरशाही शामिल होती है। कार्यान्वयन की सफलता ही सरकार की प्रभावशीलता को निर्धारित करती है, क्योंकि नीतियों के लाभ जनता तक तभी पहुँचते हैं जब उनका क्रियान्वयन कुशल और पारदर्शी तरीके से किया जाए।

204. (B) राजनीतिक व्यवस्था की क्षमता और संरचना में परिवर्तन की प्रक्रिया।
'राजनीतिक विकास' शब्द का उपयोग मुख्य रूप से उन प्रक्रियाओं के अध्ययन के लिए किया जाता है जिनके माध्यम से एक राजनीतिक व्यवस्था अपनी समस्याओं को हल करने की क्षमता और अपने संस्थानों की जटिलता को बढ़ाती है। इसमें राजनीतिक भूमिकाओं का विशिष्टीकरण, नागरिकों की सक्रिय भागीदारी में वृद्धि और व्यवस्था के भीतर न्याय व समानता की स्थापना शामिल है। यह केवल संस्थानों का वर्णन नहीं है, बल्कि यह समय के साथ शासन प्रणालियों के विकास और उनके आधुनिकीकरण की दिशा में होने वाले गतिशील परिवर्तनों का विश्लेषण करता है।

205. (A) द सिविक कल्चर
गैब्रियल आलमंड और सिडनी वर्बा की 1963 में प्रकाशित पुस्तक 'द सिविक कल्चर' राजनीतिक संस्कृति के अध्ययन में एक मील का पत्थर मानी जाती है। इस पुस्तक ने यह वैज्ञानिक आधार प्रदान किया कि लोकतंत्र की सफलता केवल कागजी संविधान पर नहीं, बल्कि नागरिकों के मनोवैज्ञानिक विश्वासों और मूल्यों के स्वरूप पर निर्भर करती है। उन्होंने सहभागी, प्रजाभावी और संकीर्ण संस्कृतियों का विश्लेषण करके यह सिद्ध किया कि एक 'नागरिक संस्कृति' ही लोकतंत्र की स्थिरता का मुख्य आधार है। यह कार्य आज भी राजनीति विज्ञान के लिए एक अनिवार्य संदर्भ ग्रंथ बना हुआ है।

206. (B) एक छोटा, एकजुट सत्तारूढ़ अल्पसंख्यक
लोकतंत्र के अभिजनवादी सिद्धांत के अनुसार, आधुनिक समाज के बड़े और जटिल होने के कारण वास्तविक सत्ता हमेशा एक छोटे, संगठित और एकजुट अल्पसंख्यक समूह के पास रहती है। यह सिद्धांत मानता है कि जनता स्वयं शासन नहीं कर सकती, बल्कि वह केवल प्रतिस्पर्धी अभिजन समूहों में से चुनाव करती है। ये अभिजन अपनी शिक्षा, संपत्ति या पद के कारण निर्णय लेने की वास्तविक शक्ति को नियंत्रित करते हैं। अतः, इस दृष्टिकोण के अनुसार, लोकतंत्र केवल शासन करने के लिए सक्षम नेतृत्व को चुनने की एक प्रक्रिया है, न कि प्रत्यक्ष जन शासन।

207. (B) एक संसदीय प्रणाली
संसदीय शासन प्रणाली की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि कार्यपालिका का निर्माण अनिवार्य रूप से विधायिका के भीतर से ही होता है। कार्यपालिका अपने पद पर बने रहने के लिए विधायिका के निरंतर विश्वास और बहुमत पर निर्भर करती है। यदि विधायिका अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे, तो सरकार गिर जाती है। यह व्यवस्था शक्तियों के संलयन और कार्यपालिका की विधायी जवाबदेही को सुनिश्चित करती है, जिससे शासन और जनता के प्रतिनिधियों के बीच एक निरंतर समन्वय और संवाद बना रहता है, जो इस प्रणाली का आधार है।

208. (D) पश्चिमी और गैर-पश्चिमी राजनीतिक प्रणालियों की तुलना की सुविधा के लिए।
संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण को 1950 और 60 के दशक में गैब्रियल आलमंड जैसे विद्वानों द्वारा विकसित किया गया था ताकि तुलनात्मक राजनीति के दायरे को संकुचित पश्चिमी संस्थानों से आगे बढ़ाया जा सके। इस दृष्टिकोण ने उन सार्वभौमिक कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया जो सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं—चाहे वे विकसित हों या विकासशील—में आवश्यक होते हैं। इससे विद्वानों को एक ही वैज्ञानिक ढांचे के अंतर्गत कबीलाई समाजों, पारंपरिक राजतंत्रों और आधुनिक लोकतंत्रों की तुलना करने की सुविधा मिली। यह दृष्टिकोण राजनीतिक विश्लेषण को अधिक समावेशी और वैश्विक बनाने के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ।

209. (B) दो देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते की बातचीत।
तुलनात्मक राजनीति का मुख्य सरोकार राज्यों के 'भीतर' की राजनीतिक प्रणालियों, व्यवहारों और संस्थानों का विश्लेषण और तुलना करना है। दो देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते की बातचीत मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन का विषय हैं। तुलनात्मक राजनीति में राष्ट्रपतियों की शक्तियों की तुलना, सैन्य तख्तापलट के घरेलू कारणों का विश्लेषण और विभिन्न देशों में चुनावी व्यवहार का अध्ययन जैसी आंतरिक

Downloaded from www.pdf.tube

इस ऐतिहासिक बदलाव ने तुलनात्मक राजनीति को एक वास्तविक वैश्विक और समावेशी अनुशासन में बदल दिया।

226. (C) अल्पतंत्र का लौह नियम
रॉबर्ट मिचल्स द्वारा प्रतिपादित 'अल्पतंत्र का लौह नियम' यह निष्कर्ष निकालता है कि प्रत्येक संगठन, चाहे वह कितना भी लोकतांत्रिक क्यों न हो, अंततः एक छोटे अल्पसंख्यक समूह के नियंत्रण में आ जाता है। मिचल्स का तर्क था कि संगठनों को चलाने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता, प्रशासन की जटिलता और नेतृत्व की मनोवैज्ञानिक श्रेष्ठता सत्ता के केंद्रीकरण को अपरिहार्य बना देती है। बहुसंख्यक सदस्य धीरे-धीरे निष्क्रिय हो जाते हैं और वे केवल नेताओं के निर्देशों का पालन करने तक सीमित रह जाते हैं। यह नियम बताता है कि पूर्ण सहभागी लोकतंत्र को स्थायी रूप से बनाए रखना किसी भी बड़े संगठन के लिए कठिन है।

227. (D) आधुनिकीकरण
लुसियन पाई ने राजनीतिक विकास की प्रक्रिया में राष्ट्रों के सम्मुख आने वाले पांच मुख्य 'संकटों' की पहचान की है: पहचान, वैधता, पैठ, भागीदारी और वितरण। ये संकट राज्य-निर्माण और राष्ट्र-निर्माण की चुनौतियों को दर्शाते हैं। 'आधुनिकीकरण' स्वयं में एक व्यापक सामाजिक-राजनीतिक प्रक्रिया है जिसके दौरान ये संकट उत्पन्न होते हैं, लेकिन इसे लुसियन पाई के विशिष्ट संकटों की सूची में एक अलग संकट के रूप में शामिल नहीं किया गया है। इन विशिष्ट चुनौतियों का सफल प्रबंधन ही किसी राजनीतिक व्यवस्था के परिपक्व विकास का वास्तविक पैमाना माना जाता है।

228. (B) अनेक मांगों को कुछ नीतिगत विकल्पों में समन्वित करते हैं।
संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक ढांचे में 'हित समूहन' का अर्थ वह प्रक्रिया है जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों की बिखरी हुई मांगों को एकीकृत करके सुसंगत नीति कार्यक्रमों में बदला जाता है। राजनीतिक दल इस कार्य में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि वे विभिन्न दबाव समूहों के हितों के बीच तालमेल बिठाते हैं और उन्हें एक स्पष्ट सरकारी कार्यसूची या चुनावी वादे के रूप में प्रस्तुत करते हैं। यह प्रक्रिया शासन को सरल और प्रबंधनीय बनाती है, जिससे राजनीतिक व्यवस्था अराजकता से बचती है और स्पष्ट नीतिगत दिशा प्राप्त करती है।

229. (B) P-2, Q-4, R-1, S-3
तुलनात्मक राजनीति की विभिन्न महत्वपूर्ण अवधारणाएं उनके प्रणेताओं के साथ गहराई से जुड़ी हुई हैं। सैमुअल हंटिंगटन ने विकासशील देशों में अस्थिरता को समझाने के लिए 'राजनीतिक पतन' का विचार दिया। आलमंड और वर्बा ने 'नागरिक संस्कृति' के माध्यम से लोकतंत्र के मनोवैज्ञानिक आधारों का विश्लेषण किया। डेविड ईस्टन ने राजनीति को एक गतिशील 'राजनीतिक व्यवस्था' के रूप में देखने का वैज्ञानिक ढांचा प्रदान किया। रॉबर्ट मिचल्स ने संगठनों के भीतर सत्ता के केंद्रीकरण के लिए 'अल्पतंत्र का लौह नियम' प्रतिपादित किया, जो नेतृत्व की प्रकृति को स्पष्ट करता है।

230. (B) अनुसंधान में तथ्यों और मूल्यों के बीच सख्त पृथक्करण।
20वीं सदी के मध्य में उभरे 'व्यवहारवादी दृष्टिकोण' ने राजनीति विज्ञान को एक वस्तुनिष्ठ विज्ञान बनाने के लिए शोध में तथ्यों और मूल्यों के बीच सख्त पृथक्करण पर जोर दिया। इस दृष्टिकोण का तर्क था कि विद्वानों को अपनी व्यक्तिगत प्राथमिकताओं या 'क्या होना चाहिए' के बजाय केवल अवलोकन योग्य और मापने योग्य डेटा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। वैज्ञानिक पद्धतियों और आनुभविक शोध के प्रयोग से इसका उद्देश्य राजनीतिक व्यवहार के सार्वभौमिक सिद्धांतों का निर्माण करना था। इस बदलाव ने तुलनात्मक राजनीति को वर्णनात्मक सीमाओं से मुक्त कर अधिक विश्लेषणात्मक बनाया।

231. (B) यूनाइटेड किंगडम
'शक्तियों का संलयन' की अवधारणा का सबसे स्पष्ट उदाहरण यूनाइटेड किंगडम की संसदीय प्रणाली में मिलता है। यहाँ कार्यपालिका और विधायिका के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन नहीं होता, बल्कि कार्यपालिका के सदस्य संसद के भीतर से ही चुने जाते हैं और उसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। यह व्यवस्था सरकार और संसद के बीच निरंतर सहयोग और समन्वय सुनिश्चित करती है। इसके विपरीत, अमेरिका जैसी राष्ट्रपति प्रणाली 'शक्तियों के पृथक्करण' पर आधारित है। यूनाइटेड किंगडम का मॉडल यह दर्शाता है कि कैसे अंगों के बीच का जुड़ाव शासन में कुशलता और उत्तरदायित्व ला सकता है।

232. (A) समाज शासकों और शासितों में विभाजित है, और यह एक अपरिहार्य सामाजिक तथ्य है।
शास्त्रीय अभिजन सिद्धांतकारों, जैसे मोस्का और पेरेटो, का मूल विचार यह है कि प्रत्येक समाज स्वाभाविक रूप से दो वर्गों में विभाजित होता है: एक छोटा संगठित अल्पसंख्यक जो शासन करता है, और एक असंगठित बहुसंख्यक जनसमूह जिस पर शासन किया जाता है। वे इसे एक सार्वभौमिक और अपरिहार्य सामाजिक तथ्य मानते हैं जो इतिहास के हर काल और हर शासन प्रणाली में मौजूद रहता है। उनके अनुसार, लोकतंत्र भी इस वास्तविकता को नहीं बदल सकता; यह केवल शासक अभिजनों के चयन का तरीका बदलता है, लेकिन सत्ता का केंद्र हमेशा अल्पसंख्यक के पास ही रहता है।

233. (B) राजनीतिक आधुनिकीकरण
राजनीतिक आधुनिकीकरण एक व्यापक प्रक्रिया है जिसमें समाज के राजनीतिक जीवन का युक्तिकरण, भूमिकाओं का संरचनात्मक विभेदीकरण और संस्कृति का धर्मनिरपेक्षीकरण शामिल है। युक्तिकरण का अर्थ है प्राधिकार का तर्कसंगत आधारों पर स्थापित होना, जबकि विभेदीकरण का तात्पर्य विशिष्ट कार्यों के लिए अलग-अलग संस्थानों का उदय है। धर्मनिरपेक्षीकरण राजनीतिक मूल्यों को धार्मिक प्रभाव से मुक्त कर उन्हें तर्क और जनहित पर आधारित बनाता है। ये तीनों घटक मिलकर एक पारंपरिक समाज को आधुनिक राष्ट्र-राज्य में बदलने में मदद करते हैं, जहाँ शासन अधिक कुशल और पारदर्शी होता है।

NODIA

218. (B) संकीर्ण, प्रजाभावी और सहभागी
आलमंड और वर्बा के 'नागरिक संस्कृति' मॉडल के अनुसार, एक स्थिर लोकतंत्र के लिए संकीर्ण, प्रजाभावी और सहभागी राजनीतिक अभिवृत्तियों का एक संतुलित मिश्रण होना आवश्यक है। सहभागी तत्व नागरिकों को सक्रिय बनाते हैं, प्रजाभावी तत्व शासन के प्रति आज्ञाकारिता सुनिश्चित करते हैं, और संकीर्ण तत्व स्थानीय निष्ठाओं के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। यह संस्कृति यह सुनिश्चित करती है कि सरकार के पास प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए पर्याप्त स्वायत्तता हो और साथ ही वह जनता के प्रति उत्तरदायी और मर्यादित भी बनी रहे, जो लोकतांत्रिक सफलता की कुंजी है।

219. (B) कार्यकारी और विधायी शाखाएं पृथक रूप से निर्वाचित और स्वतंत्र होती हैं।
राष्ट्रपति प्रणाली की सबसे परिभाषित विशेषता 'शक्तियों का पृथक्करण' है। इस व्यवस्था में, कार्यपालिका और विधायिका का चुनाव अलग-अलग होता है और उनके पास वैधता के अपने स्वतंत्र स्रोत होते हैं। राष्ट्रपति विधायिका का सदस्य नहीं होता और न ही वह अपने पद के लिए विधायी विश्वास पर निर्भर करता है। यह स्वायत्तता राष्ट्रपति को एक निश्चित कार्यकाल और निर्णय लेने की स्वतंत्रता प्रदान करती है। साथ ही, 'नियंत्रण और संतुलन' की व्यवस्था यह सुनिश्चित करती है कि ये दोनों स्वतंत्र शाखाएं अपनी संवैधानिक सीमाओं के भीतर रहकर कार्य करें।

220. (B) राजनीतिक अभिविन्यास प्राप्त करने की आजीवन प्रक्रिया।
राजनीतिक समाजीकरण वह निरंतर सामाजिक और मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति बचपन से लेकर मृत्यु तक राजनीति के प्रति अपनी धारणाओं, विश्वासों, मूल्यों और कौशलों को विकसित करता है। यह प्रक्रिया केवल जानकारी प्राप्त करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के भीतर एक राजनीतिक पहचान और व्यवस्था के प्रति एक विशिष्ट नजरिया पैदा करती है। परिवार, मित्र, शिक्षण संस्थान और मीडिया इस कार्य के मुख्य अभिकर्ता हैं। यह सुनिश्चित करता है कि समाज की राजनीतिक संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सफलतापूर्वक हस्तांतरित हो।

221. (A) 2, 4, 3, 1
शास्त्रीय और आधुनिक अभिजन सिद्धांतकारों के कार्यों का कालक्रम उनके विचारों के विकास की दिशा को दर्शाता है। सर्वप्रथम 19वीं सदी के अंत में गेटानो मोस्का ने 'शासक वर्ग' का विचार दिया। इसके तुरंत बाद विल्फ्रेडो पेरेटो ने अभिजनों के संचलन और मनोवैज्ञानिक गुणों पर प्रकाश डाला। 1911 में रॉबर्ट मिचल्स ने 'अल्पतंत्र का लौह नियम' प्रतिपादित किया, जो संगठनात्मक शक्ति पर केंद्रित था। अंततः 1956 में सी. राइट मिल्स ने 'द पावर एलीट' के माध्यम से आधुनिक अमेरिका की संस्थागत शक्ति संरचना का विश्लेषण प्रस्तुत किया, जिसने इस क्षेत्र को नया आयाम दिया।

222. (B) राजनीतिक व्यवस्था के समक्ष आवश्यकताओं और मांगों को व्यक्त करने की प्रक्रिया।
संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण में 'हित प्रकटीकरण' वह प्राथमिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समाज के विभिन्न व्यक्ति और समूह अपनी विशिष्ट मांगों, चिंताओं और आकांक्षाओं को नीति निर्माताओं तक पहुँचाते हैं। यह कार्य अक्सर दबाव समूहों, श्रमिक संघों और नागरिक समाज के संगठनों द्वारा किया जाता है। यह राजनीतिक व्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण 'आगत' का कार्य करता है, क्योंकि इसके बिना सरकार को जनता की वास्तविक समस्याओं और प्राथमिकताओं का पता नहीं चल पाएगा। प्रभावी हित प्रकटीकरण शासन की लोकतांत्रिक प्रभावकारिता को सुदृढ़ बनाने में सहायक होता है।

223. (B) इसमें वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग करते हुए राज्यों के भीतर सभी राजनीतिक गतिविधियों का अध्ययन शामिल है।
आधुनिक तुलनात्मक राजनीति का दायरा अत्यंत व्यापक और विश्लेषणात्मक है। यह केवल औपचारिक संविधानों या प्रमुख शक्तियों के अध्ययन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें दुनिया के सभी राज्यों के भीतर होने वाली राजनीतिक गतिविधियों, प्रक्रियाओं और व्यवहारों का वैज्ञानिक विश्लेषण शामिल है। आधुनिक विद्वान आनुभविक डेटा, सांख्यिकी और समाजशास्त्रीय उपकरणों का उपयोग करते हुए यह समझने का प्रयास करते हैं कि राजनीतिक संस्थाएं वास्तव में व्यवहार में कैसे कार्य करती हैं। यह वैश्विक स्तर पर समानताओं और विविधताओं की खोज करके राजनीति के सामान्य सिद्धांतों को विकसित करने के प्रति समर्पित है।

224. (B) वह निकाय है जिससे कार्यपालिका निर्मित होती है और जिसके प्रति वह जवाबदेह होती है।
संसदीय प्रणाली में विधायिका और कार्यपालिका के बीच का संबंध 'शक्तियों के संलयन' पर आधारित होता है। यहाँ विधायिका वह मुख्य स्रोत है जिससे सरकार या कार्यपालिका का चयन किया जाता है। प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल संसद के सदस्य होते हैं और वे अपने पद पर बने रहने के लिए संसद के निचले सदन के निरंतर विश्वास और बहुमत पर निर्भर करते हैं। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि कार्यपालिका अपनी प्रत्येक नीति और कार्य के लिए सीधे तौर पर जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी बनी रहे, जो संसदीय लोकतंत्र का आधारभूत सिद्धांत है।

225. (A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं और कथन II, कथन I की सही व्याख्या है।
द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात तुलनात्मक राजनीति के अनुशासन में एक महान विस्तार देखा गया, जिसका मुख्य कारण एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में वि-औपनिवेशीकरण की लहर थी। इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप कई नए स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ, जिनकी राजनीतिक चुनौतियां और संस्कृतियाँ पश्चिमी यूरोप से भिन्न थीं। इन विविध उदाहरणों ने विद्वानों को केवल पश्चिमी मॉडलों से बाहर निकलकर अधिक व्यापक और वैज्ञानिक सिद्धांतों को विकसित करने के लिए प्रेरित किया।

Click Here to Buy book on Amazon

व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा और न्याय की स्थापना के लिए अनिवार्य माना जाता है।

242. (D) मात्रात्मक डेटा पर अत्यधिक निर्भर होने के लिए।
तुलनात्मक राजनीति के पारंपरिक दृष्टिकोण की आलोचना उसके अत्यधिक औपचारिक, कानूनी और वर्णनात्मक होने के लिए की गई थी। इसे यूरोप-केंद्रित भी माना गया क्योंकि यह मुख्य रूप से पश्चिमी संस्थानों तक सीमित था। हालाँकि, यह कहना अनुचित है कि इसकी आलोचना मात्रात्मक डेटा पर निर्भर होने के लिए की गई थी, क्योंकि पारंपरिक दृष्टिकोण में सांख्यिकीय और मात्रात्मक विधियों का सर्वथा अभाव था। मात्रात्मक डेटा और वैज्ञानिक पद्धतियों पर जोर देना आधुनिक व्यवहारवादी दृष्टिकोण की मुख्य विशेषता है, जो पारंपरिक दृष्टिकोण की सीमाओं को दूर करने के लिए उभरा था।

243. (C) सरकार की प्रशासनिक पहुंच को दूरस्थ क्षेत्रों तक विस्तारित करना।
लुसियन पाई द्वारा वर्णित 'पैठ का संकट' उस चुनौती को संदर्भित करता है जहाँ एक नई या विकासशील केंद्र सरकार पूरे देश की सीमाओं के भीतर अपने प्रशासनिक आदेशों और कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने में कठिनाई महसूस करती है। यह संकट तब गहरा होता है जब राज्य के पास दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुँचने के लिए पर्याप्त बुनियादी ढाँचा, कुशल नौकरशाही और संचार तंत्र नहीं होता। इस संकट का समाधान करना राज्य-निर्माण के लिए अनिवार्य है क्योंकि इसके बिना सरकार समाज में वास्तविक परिवर्तन नहीं ला सकती और न ही प्रभावी ढंग से शासन कर सकती है।

244. (B) जोसेफ शुम्पेटर
'प्रतिस्पर्धी अभिजनवाद' के सिद्धांत को विशेष रूप से जोसेफ शुम्पेटर ने अपनी पुस्तक 'कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी' में व्यक्त किया था। शुम्पेटर का तर्क था कि आधुनिक लोकतंत्र में जनता द्वारा शासन एक व्यावहारिक मिथक है। उन्होंने लोकतंत्र को एक ऐसी विधि के रूप में पुनर्परिभाषित किया जिसमें जनता की भूमिका केवल उन नेताओं या अभिजनों के बीच चुनाव करने तक सीमित है जो सत्ता के लिए एक-दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं। यहाँ लोकतंत्र का अर्थ नीतियों पर नियंत्रण नहीं, बल्कि मतों के लिए अभिजनों के बीच होने वाला एक व्यवस्थित संघर्ष है, जो शासन को वैधता देता है।

245. (A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं और कथन II, कथन I की सही व्याख्या है।
संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण ने तुलनात्मक राजनीति में एक क्रांतिकारी वैज्ञानिक आधार प्रदान किया क्योंकि इसने विविध प्रणालियों की तुलना के लिए एक तटस्थ ढांचा तैयार किया। इस दृष्टिकोण की मूल मान्यता यह है कि प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था, चाहे वह कितनी भी अलग क्यों न हो, जीवित रहने के लिए कुछ सार्वभौमिक कार्य अवश्य करती है। यह विद्वानों को एक आधुनिक लोकतंत्र और एक पारंपरिक समाज की तुलना इस आधार पर करने की अनुमति देता है कि वे अपने-अपने ढंग से इन अनिवार्य कार्यों को कैसे पूरा करते हैं, जिससे विश्लेषण अधिक व्यावहारिक बनता है।

246. (A) करों का भुगतान और विधि का पालन।
डेविड ईस्टन के व्यवस्था विश्लेषण मॉडल में 'समर्थन' एक महत्वपूर्ण आगत है जो राजनीतिक व्यवस्था को स्थिरता प्रदान करता है। समर्थन के उदाहरणों में नागरिकों द्वारा नियमित रूप से करों का भुगतान करना, राज्य के कानूनों का स्वेच्छा से पालन करना, चुनावों में मतदान करना और राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति सम्मान दिखाना शामिल है। यह समर्थन ही व्यवस्था को वह शक्ति और वैधता प्रदान करता है जिसके आधार पर वह मांगों को निर्णयों में बदल पाती है। यदि समर्थन का स्तर गिर जाता है, तो व्यवस्था में तनाव बढ़ जाता है और उसकी स्थिरता खतरे में पड़ सकती है।

247. (D) उनके पास वैधता के पृथक स्रोत और स्वतंत्रता होती है।
राष्ट्रपति प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका के बीच सबसे प्रमुख अंतर 'शक्तियों के पृथक्करण' के सिद्धांत में निहित है। यहाँ राष्ट्रपति और संसद दोनों का चुनाव अलग-अलग निर्वाचक मंडलों द्वारा किया जाता है, जिससे उनके पास वैधता के अपने स्वतंत्र स्रोत होते हैं। राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता और न ही वह अपने पद के लिए विधायी बहुमत पर निर्भर करता है। यह स्वायत्तता सुनिश्चित करती है कि दोनों शाखाएं एक-दूसरे के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप किए बिना स्वतंत्र रूप से कार्य करें, जबकि नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था सत्ता के दुरुपयोग को रोकती है।

248. (C) राजनीति के प्रति रखे गए व्यक्तिपरक अभिवृत्ति, विश्वास और मूल्य।
राजनीतिक संस्कृति का अध्ययन मुख्य रूप से उन आंतरिक और मनोवैज्ञानिक स्वरूपों की जांच करता है जो नागरिकों के राजनीतिक व्यवहार को गहराई से प्रभावित करते हैं। इसमें राजनीति के प्रति लोगों के विश्वास, उनकी निष्ठाएं, व्यवस्था के प्रति उनके गौरव या असंतोष की भावनाएं और उनके लोकतांत्रिक मूल्यों का विश्लेषण किया जाता है। यह दृष्टिकोण केवल बाहरी कानूनों पर नहीं, बल्कि उन व्यक्तिपरक धारणाओं पर ध्यान केंद्रित करता है जो यह तय करती हैं कि कोई राजनीतिक व्यवस्था कितनी स्थिर और प्रभावी होगी। यह राजनीति के अध्ययन में एक अत्यंत महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक आयाम जोड़ता है।

249. (A) एक सिद्धांत जो लोकतंत्र को सत्ता के लिए अभिजनों के बीच एक प्रतिस्पर्धी संघर्ष के रूप में परिभाषित करता है।
लोकतंत्र का अभिजनवादी सिद्धांत इस यथार्थवादी विचार पर आधारित है कि आधुनिक और जटिल समाजों में प्रत्यक्ष जन-शासन संभव नहीं है। यह लोकतंत्र को एक ऐसी 'प्रक्रियात्मक व्यवस्था' के रूप में देखता है जहाँ जनता की भूमिका केवल उन प्रतिस्पर्धी नेताओं या अभिजनों का चुनाव करने तक सीमित है जो उन पर शासन करने का अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं। जोसेफ शुम्पेटर जैसे विद्वानों के अनुसार, लोकतंत्र का अर्थ नीतियों पर जनता का सीधा नियंत्रण नहीं, बल्कि नेतृत्व के लिए होने वाला एक व्यवस्थित राजनीतिक संघर्ष है। यह दृष्टिकोण लोकतंत्र को एक व्यवहार्य शासन पद्धति के रूप में प्रस्तुत करता है।

Downloaded from www.pdf.tube

266. (A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं और कथन II, कथन I की सही व्याख्या है।
संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका और विधायिका के बीच एक गहरा कार्यात्मक जुड़ाव होता है। सरकार का जन्म विधायिका के भीतर से होता है और वह तब तक ही सत्ता में रह सकती है जब तक उसे निचले सदन का बहुमत प्राप्त हो। 'अविश्वास प्रस्ताव' वह संवैधानिक उपकरण है जिसके माध्यम से विधायिका यह सुनिश्चित करती है कि सरकार अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न करे। यदि सदन अविश्वास व्यक्त करता है, तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। यह तंत्र संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका की निरंतर जवाबदेही और शासन की लोकतांत्रिक वैधता को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है।

267. (D) अमेरिकी कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित होता है, जबकि यूनाइटेड किंगडम की कार्यपालिका का कार्यकाल विधायी विश्वास पर निर्भर करता है।
संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम की कार्यपालिका प्रणालियों के बीच सबसे मौलिक अंतर उनके कार्यकाल की स्थिरता और जवाबदेही में है। अमेरिकी राष्ट्रपति प्रणाली में राष्ट्रपति का कार्यकाल संवैधानिक रूप से निश्चित होता है और वह विधायिका से स्वतंत्र होता है। इसके विपरीत, यूनाइटेड किंगडम की संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल का कार्यकाल हाउस ऑफ कॉमन्स के निरंतर विश्वास पर निर्भर करता है; यदि वे बहुमत खो देते हैं, तो उन्हें पद छोड़ना पड़ता है। यह अंतर राष्ट्रपति प्रणाली को अधिक स्थिरता प्रदान करता है, जबकि संसदीय प्रणाली को अधिक उत्तरदायी बनाता है।

268. (B) विकास के संकट, जैसे पहचान, वैधता और भागीदारी।
लुसियन पाई ने राजनीतिक विकास के अध्ययन में एक अत्यंत प्रभावशाली ढांचा प्रदान किया, जिसमें उन्होंने राष्ट्र-निर्माण और राज्य-निर्माण के दौरान आने वाले पांच मूलभूत संकटों की पहचान की। इनमें पहचान, वैधता, पैठ, भागीदारी और वितरण के संकट शामिल हैं। पाई का तर्क था कि किसी भी व्यवस्था का सफल विकास इन संकटों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने और हल करने की उसकी क्षमता पर निर्भर करता है। यह दृष्टिकोण विशेष रूप से वि-औपनिवेशीकरण के बाद उभरे नए राष्ट्रों की जटिल चुनौतियों और उनके विकास की गति को समझने के लिए एक व्यवस्थित आधार प्रदान करता है।

269. (C) राजनीतिक संचार
राजनीतिक संचार वह महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें सूचनाओं, संदेशों और प्रतीकों का प्रवाह समाज और राजनीतिक व्यवस्था के बीच निरंतर होता रहता है। यह सूचना का वह प्रवाह है जो जनमत के निर्माण, नागरिकों की जागरूकता और राजनीतिक निर्णयों को गहराई से प्रभावित करता है। संचार के माध्यम जैसे समाचार पत्र, दूरदर्शन और अब डिजिटल प्लेटफॉर्म इस प्रक्रिया के मुख्य वाहक हैं। प्रभावी राजनीतिक संचार यह सुनिश्चित करता है कि सरकार की नीतियां जनता तक पहुँचें और जनता की प्रतिक्रियाएं सरकार तक, जो किसी भी सक्रिय राजनीतिक व्यवस्था की कार्यक्षमता और उसकी जवाबदेही का अनिवार्य आधार है।

270. (B) P-2, Q-3, R-1, S-4
आलमंड और वर्बा ने राजनीतिक संस्कृति के विभिन्न प्रकारों को नागरिकों के राजनीतिक अभिविन्यास के आधार पर वर्गीकृत किया है। संकीर्ण संस्कृति में नागरिक पूरी व्यवस्था के प्रति अनभिज्ञ होते हैं। प्रजाभावी संस्कृति में वे सरकार के निर्गत कार्यों के प्रति जागरूक होते हैं लेकिन स्वयं निष्क्रिय रहते हैं। सहभागी संस्कृति में नागरिक व्यवस्था के प्रति जागरूक और आगत प्रक्रियाओं में सक्रिय होते हैं। 'नागरिक संस्कृति' इन तीनों अभिविन्यासों का एक संतुलित मिश्रण है, जो लोकतंत्र की स्थिरता और प्रभावशीलता के लिए सबसे आदर्श माना जाता है।

271. (B) अभिजनवाद
सी. राइट मिल्स की प्रसिद्ध पुस्तक 'द पावर एलीट' अभिजनवादी सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। मिल्स ने इस विचार को चुनौती दी कि अमेरिकी लोकतंत्र में शक्ति व्यापक रूप से जनता या विविध समूहों के बीच बिखरी हुई है। उन्होंने तर्क दिया कि वास्तविक शक्ति कॉर्पोरेट, सैन्य और राजनीतिक संस्थानों के शीर्ष पर बैठे एक छोटे और एकीकृत समूह के पास है। यह समूह महत्वपूर्ण राष्ट्रीय नीतियों को नियंत्रित करता है, जो सामान्य लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के प्रभाव से बाहर होता है। यह विश्लेषण आधुनिक समाजों में सत्ता के संस्थागत केंद्रीकरण को स्पष्ट रूप से उजागर करता है।

272. (C) राजनीतिक स्थितियों में व्यक्ति कैसा व्यवहार करते हैं, इसका अध्ययन करने के लिए आनुभविक विधियों का उपयोग करना।
20वीं सदी के मध्य में उभरे 'व्यवहारवादी आंदोलन' ने तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन को वर्णनात्मक और कानूनी सीमाओं से मुक्त किया। इसने राजनीतिक अभिनेताओं—जैसे मतदाताओं, राजनेताओं और समूहों—के वास्तविक और अवलोकन योग्य व्यवहार के अध्ययन पर बल दिया। आनुभविक विधियों और वैज्ञानिक डेटा का उपयोग करते हुए, इसका लक्ष्य राजनीति के ऐसे सामान्य सिद्धांत विकसित करना था जिन्हें सिद्ध किया जा सके। यह दृष्टिकोण 'क्या होना चाहिए' के बजाय 'क्या है' पर ध्यान केंद्रित करता है, जिससे राजनीति विज्ञान एक अधिक वस्तुनिष्ठ और वैज्ञानिक सामाजिक अनुशासन के रूप में स्थापित हुआ।

273. (B) नियम-अनुप्रयोग
सरकार के कार्यकारी अंग का मुख्य और प्राथमिक उत्तरदायित्व 'नियम-अनुप्रयोग' है। इसका अर्थ है विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों और नीतियों को समाज में प्रभावी ढंग से लागू करना और प्रशासनिक मशीनरी का संचालन करना। कार्यपालिका वह अंग है जो शासन का दैनिक कार्य देखती है, कानून व्यवस्था बनाए रखती है और सार्वजनिक सेवाओं को जनता तक पहुँचाती है। जबकि विधायिका नियम बनाती है और न्यायपालिका उनका अधिनिर्णयन करती है, कार्यपालिका उन नियमों के वास्तविक

NODIA

अराजकता से बचाकर उसे एक स्पष्ट दिशा और प्रभावशीलता प्रदान करने के लिए अनिवार्य है।

258. (B) डेविड ईस्टन
"समाज के लिए मूल्यों का आधिकारिक आवंटन" राजनीति की यह अत्यंत प्रसिद्ध परिभाषा डेविड ईस्टन द्वारा दी गई थी। ईस्टन के अनुसार, राजनीति एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ समाज के महत्वपूर्ण संसाधनों, पुरस्कारों और अधिकारों का वितरण सरकार द्वारा किया जाता है। 'आधिकारिक' शब्द का अर्थ है कि ये निर्णय पूरे समाज पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होते हैं। यह परिभाषा राजनीति को केवल संस्थानों के अध्ययन से ऊपर उठाकर एक गतिशील सामाजिक प्रक्रिया के रूप में देखती है जहाँ सत्ता का उपयोग सामूहिक हितों और संघर्षों के समाधान के लिए किया जाता है।

259. (B) शक्ति पृथक्करण बनाम शक्तियों के संलयन की प्रणालियाँ।
कार्यपालिका और विधायिका के बीच संबंधों का तुलनात्मक विश्लेषण मुख्य रूप से इस बात की जांच करता है कि शासन की ये दो शाखाएं एक-दूसरे से किस प्रकार जुड़ी या अलग हैं। इसमें 'शक्ति पृथक्करण' और 'शक्तियों के संलयन' के मॉडलों का अध्ययन किया जाता है। यह विश्लेषण यह समझने में मदद करता है कि विभिन्न देशों ने सरकार की जवाबदेही, स्थिरता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए कौन से संवैधानिक तरीके अपनाए हैं। यह अंगों के बीच के संतुलन और शासन की कार्यशैली को स्पष्ट करने का आधार है।

260. (D) 1, 2 और 3
सैमुअल हंटिंगटन ने राजनीतिक विकास के अपने सिद्धांत में तर्क दिया कि केवल तीव्र सामाजिक परिवर्तन और बढ़ती भागीदारी प्रगति की गारंटी नहीं देते। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि राजनीतिक संस्थानों का विकास सामाजिक गतिशीलता की तुलना में धीमा है, तो यह 'राजनीतिक पतन' और अस्थिरता की ओर ले जाएगा। हंटिंगटन ने आधुनिकीकरण सिद्धांत की इस आशावादी धारणा की आलोचना की कि विकास हमेशा लोकतंत्र की ओर ले जाता है। उन्होंने व्यवस्था और स्थिरता को प्राथमिकता दी और तर्क दिया कि सफल विकास के लिए मजबूत और प्रभावी संस्थानों का होना अनिवार्य शर्त है।

261. (C) किसी जनसंख्या के भीतर राजनीति के प्रति सामूहिक अभिवृत्तियाँ, विश्वास और भावनाएं।
राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा किसी समाज के उन व्यक्तिपरक और मनोवैज्ञानिक स्वरूपों को संदर्भित करती है जो राजनीति और शासन के प्रति नागरिकों के दृष्टिकोण को निर्धारित करते हैं। इसमें व्यवस्था के प्रति उनके विश्वास, वफादारी या उदासीनता की सामूहिक भावनाएं शामिल होती हैं। यह संस्कृति नागरिकों के राजनीतिक व्यवहार को गहराई से प्रभावित करती है और यह तय करती है कि वे सत्ता में कैसे भाग लेते हैं और उसे कितनी वैधता प्रदान करते हैं। यह अवधारणा यह समझने के लिए अनिवार्य है कि क्यों एक ही प्रकार के लोकतांत्रिक संस्थान अलग-अलग देशों में अलग-अलग परिणाम देते हैं।

262. (A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।
शास्त्रीय अभिजन सिद्धांतकारों, जैसे गेटानो मोस्का और विल्फ्रेडो पेरेटो, का यह मूल मत था कि प्रत्येक समाज में शक्ति हमेशा एक छोटे अल्पसंख्यक समूह के पास होती है, जो शासन करता है। उन्होंने तर्क दिया कि यह अल्पसंख्यक वर्ग बहुसंख्यक जनसमूह की तुलना में बेहतर संगठित, शिक्षित और संसाधनों से संपन्न होता है। उनकी संगठनात्मक श्रेष्ठता ही उन्हें सत्ता पर नियंत्रण बनाए रखने और जनसमूह को निर्देशित करने की अनुमति देती है। उनके अनुसार, यह विभाजन एक अपरिहार्य सामाजिक सच्चाई है जिसे लोकतंत्र भी पूरी तरह से समाप्त नहीं कर सकता है।

263. (C) कानूनों और सरकारी कार्यों की संवैधानिकता निर्धारित करते हैं।
तुलनात्मक राजनीति में 'न्यायिक समीक्षा' न्यायपालिका की वह अत्यंत महत्वपूर्ण शक्ति है जिसके माध्यम से न्यायालय विधायिका द्वारा पारित कानूनों और कार्यपालिका के निर्णयों की संवैधानिक वैधता की जाँच करते हैं। यदि कोई कानून या कार्य संविधान के प्रावधानों या उसकी मूल भावना का उल्लंघन करता है, तो न्यायपालिका उसे शून्य या असंवैधानिक घोषित कर सकती है। यह शक्ति संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखने, शक्तियों के संतुलन को सुदृढ़ करने और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसी भी कानून-आधारित शासन व्यवस्था में अनिवार्य स्तंभ मानी जाती है।

264. (C) वर्ग संघर्ष
मार्क्सवादी दृष्टिकोण राजनीतिक परिघटनाओं का विश्लेषण मुख्य रूप से 'वर्ग संघर्ष' के माध्यम से करता है। इस सिद्धांत के अनुसार, समाज का आर्थिक ढांचा ही उसकी राजनीतिक और कानूनी व्यवस्था को आकार देता है। राजनीति को स्वतंत्र व्यक्तियों के बीच की प्रतिस्पर्धा के बजाय आर्थिक रूप से प्रभावी शासक वर्ग और शोषित वर्ग के बीच के निरंतर संघर्ष के रूप में देखा जाता है। राज्य और उसके संस्थान शासक वर्ग के हितों की रक्षा करने और यथास्थिति बनाए रखने के साधन मात्र होते हैं। अतः, वास्तविक राजनीतिक परिवर्तन केवल तभी संभव है जब वर्ग संबंधों में क्रांतिकारी बदलाव आए।

265. (C) आनुभविक विश्लेषण और सिद्धांत-निर्माण के प्रति प्रतिबद्धता।
आधुनिक तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति पारंपरिक दृष्टिकोण से इस मायने में भिन्न है कि यह अब केवल औपचारिक संस्थानों के वर्णन और आदर्शात्मक चर्चा तक सीमित नहीं है। आधुनिक विद्वान आनुभविक विश्लेषण, वैज्ञानिक पद्धतियों और वस्तुनिष्ठ डेटा के आधार पर तथ्यों को समझने और सिद्धांतों का निर्माण करने के प्रति प्रतिबद्ध हैं। वे राजनीति के वास्तविक व्यवहार और अनौपचारिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं ताकि यह समझाया जा सके कि विभिन्न प्रणालियाँ कैसे और क्यों कार्य करती हैं। यह बदलाव इस विषय को अधिक सटीक और वास्तव में एक वैश्विक सामाजिक विज्ञान बनाता है।

Click Here to Buy book on Amazon

250. (B) P-3, Q-1, R-4, S-2
तुलनात्मक राजनीति की विभिन्न दृष्टिकोण अपनी विशिष्ट मूल अवधारणाओं के लिए जाने जाते हैं। पारंपरिक दृष्टिकोण मुख्य रूप से औपचारिक-कानूनी संस्थानों के अध्ययन पर केंद्रित था। डेविड ईस्टन द्वारा प्रस्तुत व्यवस्था दृष्टिकोण आगत, निर्गत और प्रतिपुष्टि की प्रक्रिया पर बल देता है। गैब्रियल आलमंड का संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण आगत और निर्गत कार्यों का विश्लेषण करता है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण समाज को आर्थिक आधार और राजनीतिक अधिसंरचना के बीच के संबंध के रूप में देखता है। ये सभी सिद्धांत राजनीति की जटिलताओं को समझने के लिए विविध और महत्वपूर्ण ढांचा प्रदान करते हैं।

251. (C) अवलोकन योग्य राजनीतिक व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन।
20वीं सदी के मध्य में उभरे 'व्यवहारवादी आंदोलन' ने तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में एक वैज्ञानिक क्रांति की। इसने दार्शनिक चिंतन और केवल कानूनी संस्थानों के वर्णन के स्थान पर 'वास्तविक राजनीतिक व्यवहार' के अध्ययन पर जोर दिया। इस दृष्टिकोण का लक्ष्य राजनीतिक अभिनेताओं—जैसे मतदाताओं, नेताओं और समूहों—की क्रियाओं का अवलोकन और मापन करना था। वैज्ञानिक पद्धतियों और आनुभविक डेटा का उपयोग करते हुए, व्यवहारवाद ने राजनीति के ऐसे सिद्धांतों का निर्माण करने का प्रयास किया जिनका परीक्षण किया जा सके, जिससे यह विषय अधिक वस्तुनिष्ठ और यथार्थवादी बन गया।

252. (B) शक्ति विधायिका से कार्यपालिका और नौकरशाही की ओर स्थानांतरित हो गई है।
'विधायिका का पतन' सिद्धांत यह तर्क देता है कि आधुनिक शासन व्यवस्था में नीति निर्माण और निर्णय लेने की वास्तविक शक्ति धीरे-धीरे निर्वाचित सदनों से हटकर कार्यपालिका और तकनीकी नौकरशाही के हाथों में केंद्रित हो गई है। आधुनिक राज्यों की बढ़ती जटिलता और त्वरित निर्णय लेने की आवश्यकता ने कार्यपालिका के प्रभाव को बढ़ा दिया है। हालाँकि विधायिकाएं अभी भी कानून बनाती हैं, लेकिन उनके पास अब कार्यपालिका की गतिविधियों पर वैसा प्रभावी नियंत्रण और सूक्ष्म निगरानी नहीं रह गई है जैसा पहले हुआ करती थी, जो लोकतांत्रिक संतुलन के लिए एक चुनौती मानी जाती है।

253. (A) राजनीति और सरकार के पारंपरिक स्वरूप से आधुनिक स्वरूप की ओर ले जाती है।
राजनीतिक आधुनिकीकरण एक व्यापक सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन की प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक समाज पारंपरिक शासन संरचनाओं से हटकर आधुनिक संस्थानों को अपनाता है। इसमें शासन के प्राधिकार का युक्तिकरण, राजनीतिक भूमिकाओं का विशिष्टीकरण और नागरिकों की राजनीतिक भागीदारी में व्यापक वृद्धि शामिल है। यह प्रक्रिया समाज को अधिक जागरूक और कार्यात्मक बनाती है, जहाँ कबीलाई या वंशानुगत वफादारियों का स्थान राष्ट्र-राज्य के प्रति संवैधानिक निष्ठा ले लेती है। इसका मुख्य उद्देश्य राजनीतिक व्यवस्था की चुनौतियों का सामना करने की क्षमता बढ़ाना और शासन को अधिक कुशल और पारदर्शी बनाना है।

254. (D) न्यायपालिका
राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया में वे संस्थान शामिल होते हैं जो नागरिकों के राजनीतिक मूल्यों, विश्वासों और व्यवहार को आकार देते हैं। परिवार, विद्यालय और जनसंचार माध्यम इसके प्रमुख और सक्रिय अभिकर्ता हैं जो निरंतर सूचनाओं और संस्कारों का संचार करते हैं। न्यायपालिका का मुख्य कार्य कानूनों की व्याख्या करना और न्याय प्रदान करना है, और यद्यपि इसके निर्णय समाज को प्रभावित करते हैं, लेकिन इसे सामान्यतः राजनीतिक समाजीकरण का एक विशिष्ट या प्राथमिक अभिकर्ता नहीं माना जाता है। समाजीकरण एक सीखने की प्रक्रिया है, जबकि न्यायपालिका एक निर्णय लेने वाली संस्था है।

255. (B) बड़े पैमाने के संगठन से कुछ लोगों का शासन होता है, जिससे सहभागिता कठिन हो जाती है।
रॉबर्ट मिचल्स द्वारा प्रतिपादित 'अल्पतंत्र का लौह नियम' यह तथ्य उजागर करता है कि किसी भी बड़े संगठन में, चाहे वह कितना भी लोकतांत्रिक क्यों न हो, सत्ता का केंद्रीकरण अनिवार्य रूप से एक छोटे नेतृत्व समूह के हाथों में हो जाता है। संगठन चलाने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता और प्रशासनिक जटिलता नेतृत्व को शक्तिशाली बनाती है, जबकि सामान्य सदस्य धीरे-धीरे निष्क्रिय हो जाते हैं। यह नियम बताता है कि बड़े संगठनों में प्रत्यक्ष जनभागीदारी को बनाए रखना व्यावहारिक रूप से असंभव है, क्योंकि निर्णय लेने की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से कुछ शीर्ष व्यक्तियों के नियंत्रण में आ जाती है।

256. (B) जिसमें केवल एक सदन होता है।
एकसदनीय विधायिका वह विधायी ढांचा है जिसमें केवल एक सदन या कक्ष होता है। इस प्रकार की व्यवस्था अक्सर छोटे और एकात्मक राज्यों में पाई जाती है जहाँ समाज अपेक्षाकृत समरूप होता है और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के लिए दूसरे सदन की आवश्यकता नहीं महसूस की जाती। एकसदनीय विधायिका का मुख्य लाभ निर्णय लेने की प्रक्रिया की गति और कम प्रशासनिक व्यय है। इसमें शक्तियों का कोई आंतरिक विभाजन नहीं होता, जिससे विधायी प्रक्रिया सरल और स्पष्ट रहती है, हालांकि इसमें जल्दबाजी में लिए गए निर्णयों के पुनरीक्षण की संभावना कम होती है।

257. (B) हित समूहन
संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक विश्लेषण में, राजनीतिक दलों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य 'हित समूहन' माना जाता है। यह वह प्रक्रिया है जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों और दबाव समूहों की विविध और कभी-कभी विरोधाभासी मांगों को एकीकृत करके कुछ स्पष्ट नीतिगत विकल्पों या व्यापक चुनावी कार्यक्रमों में बदला जाता है। दल विभिन्न हितों के बीच तालमेल बिठाते हैं और उन्हें एक ऐसी सुसंगत कार्यसूची के रूप में प्रस्तुत करते हैं जिसे सरकार द्वारा लागू किया जा सके। यह कार्य शासन को

NODIA

क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होती है, जो शासन की प्रत्यक्ष प्रभावशीलता को दर्शाता है।

274. (D) प्राधिकार के पारंपरिक स्रोतों का सुदृढ़ीकरण।
राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में प्राधिकार के पारंपरिक स्रोतों—जैसे वंशानुगत उत्तराधिकार या धार्मिक मान्यता—का सुदृढ़ीकरण नहीं होता, बल्कि उनका स्थान तर्कसंगत-कानूनी प्राधिकार ले लेता है। आधुनिकीकरण में राजनीतिक संस्कृति का धर्मनिरपेक्षीकरण, राजनीतिक संरचनाओं का विशिष्टीकरण और जनभागीदारी में व्यापक वृद्धि शामिल है। इसका लक्ष्य समाज को एक अधिक जागरूक और एकीकृत राष्ट्र-राज्य में बदलना है जहाँ शासन आधुनिक और तर्कसंगत नियमों पर आधारित हो। अतः, पारंपरिक शक्तियों का कमजोर होना और आधुनिक संस्थाओं का मजबूत होना ही इस परिवर्तन की मुख्य पहचान है।

275. (C) एक ऐसी संस्कृति जहाँ नागरिक राजनीतिक प्रक्रिया के प्रति जागरूक और उसमें सम्मिलित होते हैं।
आलमंड और वर्बा के वर्गीकरण में 'सहभागी' राजनीतिक संस्कृति उस समाज को दर्शाती है जहाँ नागरिक अपनी राजनीतिक व्यवस्था और उसकी प्रक्रियाओं के प्रति अत्यधिक जागरूक होते हैं। ऐसे नागरिक यह मानते हैं कि वे मतदान, आंदोलनों और चर्चाओं के माध्यम से सरकारी निर्णयों को प्रभावित करने की शक्ति रखते हैं। उनमें उच्च राजनीतिक प्रभावकारिता होती है और वे शासन की आगत और निर्गत दोनों गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। यह संस्कृति एक जीवंत लोकतंत्र की सफलता और नागरिकों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करती है।

276. (C) सरकार को चुनने और अधिकृत करने की एक विधि।
जोसेफ शुम्पेटर ने लोकतंत्र के 'प्रक्रियात्मक' सिद्धांत के माध्यम से इसे एक ऐसी विधि के रूप में पुनर्परिभाषित किया जिसका उद्देश्य केवल शासकों का चयन करना है। उनके अनुसार, लोकतंत्र वह व्यवस्था नहीं है जहाँ जनता शासन करती है, बल्कि यह वह प्रक्रिया है जहाँ जनता के पास प्रतिस्पर्धी नेताओं या अभिजनों के बीच चुनाव करने का अवसर होता है जो उन पर शासन करेंगे। यहाँ लोकतंत्र का सार नीतियों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण के स्थान पर मतों के लिए होने वाला एक व्यवस्थित राजनीतिक संघर्ष है। यह दृष्टिकोण लोकतंत्र को यथार्थवादी रूप में प्रस्तुत करता है।

277. (C) डेविड ईस्टन
राजनीति के 'व्यवस्था दृष्टिकोण' का प्रतिपादन मुख्य रूप से डेविड ईस्टन द्वारा किया गया था। उन्होंने राजनीति को एक गतिशील और परस्पर निर्भर राजनीतिक व्यवस्था के रूप में अवधारणाबद्ध किया जो अपने पर्यावरण के साथ निरंतर अंतःक्रिया करती है। ईस्टन ने 'आगत' को 'निर्गत' में बदलने की रूपांतरण प्रक्रिया पर बल दिया। यह दृष्टिकोण राजनीति को केवल संस्थानों के अध्ययन से ऊपर उठाकर एक वैज्ञानिक और प्रक्रियात्मक ढांचा प्रदान करता है, जो किसी भी व्यवस्था की स्थिरता और अनुकूलन क्षमता को समझने के लिए अत्यंत उपयोगी और प्रभावशाली साबित हुआ है।

278. (B) संयुक्त राज्य अमेरिका में
सरकार के अंगों के बीच 'शक्तियों के पृथक्करण' का सिद्धांत संयुक्त राज्य अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था की एक आधारभूत पहचान है। यहाँ विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को संवैधानिक रूप से एक-दूसरे से स्वतंत्र रखा गया है, और उनके पास वैधता के अपने अलग स्रोत हैं। इसके साथ ही 'नियंत्रण और संतुलन' की एक सूक्ष्म व्यवस्था भी लागू है जो यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी अंग निरंकुश न हो सके। यह मॉडल यूनाइटेड किंगडम की संसदीय प्रणाली से भिन्न है जहाँ शक्तियों का संलयन पाया जाता है, जो अमेरिकी व्यवस्था को विशिष्ट बनाता है।

279. (C) राजनीतिक समाजीकरण
राजनीतिक समाजीकरण वह निरंतर सामाजिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी समाज के राजनीतिक मूल्य, विश्वास और अभिवृत्तियाँ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सफलतापूर्वक हस्तांतरित की जाती हैं। यह प्रक्रिया नागरिक पहचान के निर्माण और राजनीतिक व्यवस्था की दीर्घकालिक निरंतरता के लिए अनिवार्य है। परिवार, विद्यालय, कार्यस्थल और जनसंचार माध्यम इसके मुख्य अभिकर्ता हैं जो व्यक्ति को राजनीतिक रूप से जागरूक और सक्रिय बनाते हैं। इसके माध्यम से ही नागरिक अपनी व्यवस्था के प्रति समर्थन की भावनाएं विकसित करते हैं, जो राजनीतिक संस्कृति के स्थायित्व का मुख्य आधार है।

280. (A) अल्पतंत्र का लौह नियम
रॉबर्ट मिचल्स की प्रसिद्ध पुस्तक 'पॉलिटिकल पार्टीज' का केंद्रीय तर्क 'अल्पतंत्र का लौह नियम' में निहित है। मिचल्स का निष्कर्ष था कि संगठन चाहे कितना भी लोकतांत्रिक क्यों न हो, उसमें सत्ता का केंद्रीकरण अनिवार्य रूप से एक छोटे नेतृत्व समूह के हाथों में हो जाता है। उन्होंने जर्मन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्ययन के माध्यम से यह सिद्ध किया कि संगठनात्मक जटिलता और नेतृत्व की विशेषज्ञता की आवश्यकता आम सदस्यों की भागीदारी को कम कर देती है। यह नियम बताता है कि बड़े संगठनों में नेतृत्व स्वाभाविक रूप से एक स्वयं को बनाए रखने वाला शक्तिशाली गुट बन जाता है।

281. (C) मूल्य और सामाजिक प्रासंगिकता
1960 के दशक के उत्तरार्ध में उभरा 'उत्तर-व्यवहारवादी' आंदोलन व्यवहारवाद की तकनीकी शुद्धता और उसकी मूल्य-तटस्थता के विरुद्ध एक शक्तिशाली प्रतिक्रिया थी। आलोचकों का तर्क था कि राजनीति विज्ञान को केवल डेटा और अमूर्त सिद्धांतों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसे समाज की वास्तविक समस्याओं और मानवीय मूल्यों के प्रति प्रासंगिक होना चाहिए। डेविड ईस्टन ने इसके माध्यम से यह आह्वान किया कि विद्वानों को सामाजिक न्याय और शांति जैसे लक्ष्यों के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। इसने राजनीति विज्ञान को फिर से मानवीय सरोकारों और सामाजिक परिवर्तन के उद्देश्यों के साथ जोड़ने का कार्य किया।

Downloaded from www.pdf.tube

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) केवल I
(B) केवल II और III
(C) केवल I और II
(D) I, II और III

31. न्यायिक सक्रियता के एक प्रमुख उपकरण, पी.आई.एल. का पूर्ण रूप क्या है?
(A) लोकहित वाद
(B) निजी हित वाद
(C) लोक सूचना कानून
(D) राजनीतिक जांच संघ

32. भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है?
(A) प्रधानमंत्री
(B) राष्ट्रपति
(C) भारत के मुख्य न्यायाधीश
(D) संसद

33. निम्नलिखित में से कौन सी एक राजनीतिक दल की प्राथमिक विशेषता है?
(A) इसका उद्देश्य केवल बाहर से सरकारी नीति को प्रभावित करना है।
(B) यह संवैधानिक साधनों के माध्यम से राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना चाहता है।
(C) यह किसी एक मुद्दे या मुद्दों के एक संकीर्ण समूह पर ध्यान केंद्रित करता है।
(D) यह लोगों के एक अनौपचारिक और असंगठित समूह के रूप में कार्य करता है।

34. भारत के निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों पर विचार करें:
1. जवाहरलाल नेहरू
2. लाल बहादुर शास्त्री
3. इंदिरा गांधी
4. मोरारजी देसाई

निम्नलिखित में से कौन उनके पहले कार्यकाल का सही कालानुक्रमिक क्रम दर्शाता है?
(A) 1, 2, 3, 4
(B) 1, 3, 2, 4
(C) 2, 1, 3, 4
(D) 1, 2, 4, 3

35. 'दबाव समूह' शब्द को सबसे अच्छी तरह से इस प्रकार परिभाषित किया गया है:
(A) एक संगठन जो सरकार बनाने के लिए चुनाव लड़ता है।
(B) एक संगठन जो सत्ता प्राप्त करने की कोशिश किए बिना सरकारी नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करता है।
(C) नीति निर्माण के लिए एक संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त निकाय।
(D) किसी विशिष्ट कानून के खिलाफ विरोध करने के लिए लोगों का एक अस्थायी जमावड़ा।

36. निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें।
कथन I: जनमत सरकार को उत्तरदायी बनाकर लोकतंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
कथन II: मीडिया जनमत को आकार देने और व्यक्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण माध्यमों में से एक है।
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
(D) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।

37. स्वतंत्रता के बाद के भारत में एक महत्वपूर्ण किसान आंदोलन, नक्सलबाड़ी विद्रोह, मुख्य रूप से किस मुद्दे से जुड़ा था?
(A) जमींदारी का उन्मूलन
(B) कृषि उत्पादों पर उच्च कराधान
(C) भूमि अधिकार और किसानों का शोषण
(D) बड़े बांधों का निर्माण

38. भारत में संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव कराने की शक्ति किसमें निहित है?
(A) भारत के राष्ट्रपति
(B) भारत का निर्वाचन आयोग
(C) प्रधानमंत्री कार्यालय
(D) भारत का सर्वोच्च न्यायालय

39. निम्नलिखित सूचियों का मिलान करें और सही विकल्प चुनें।
सूची I: (अवधारणा)
P. चुनावी व्यवहार
Q. चुनावी सुधार
R. जनमत
S. दबाव समूह
सूची II: (विवरण)
1. चुनाव प्रक्रिया में सुधार के उपाय
2. नीति को प्रभावित करने की कोशिश करने वाला समूह
3. लोग चुनाव में कैसे मतदान करते हैं इसका अध्ययन
4. किसी मुद्दे पर लोगों का सामूहिक दृष्टिकोण
(A) P-1, Q-3, R-2, S-4
(B) P-3, Q-1, R-4, S-2
(C) P-3, Q-2, R-4, S-1
(D) P-4, Q-1, R-3, S-2

40. भारत में चुनावी व्यवहार को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख कारक निम्नलिखित में से कौन सा है?
(A) जाति, वर्ग और धर्म सहित विभिन्न कारकों की एक जटिल अंतःक्रिया
(B) केवल मतदाता की औपचारिक शिक्षा का स्तर और व्यावसायिक योग्यता
(C) केवल एक विकसित शहरी क्षेत्र के भीतर मतदाता का निवास स्थान
(D) अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक माहौल के भीतर पाए जाने वाले

NODIA

290. (A) एक ऐसी व्यवस्था जिसमें एक निर्वाचित राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल का नेतृत्व करने वाला प्रधानमंत्री होता है।
अर्ध-राष्ट्रपति प्रणाली, जैसा कि फ्रांस में देखी जाती है, राष्ट्रपति और संसदीय शासन प्रणालियों का एक अनूठा संवैधानिक मिश्रण है। इसमें राष्ट्रपति सीधे जनता द्वारा निर्वाचित होता है और उसके पास राष्ट्राध्यक्ष के रूप में महत्वपूर्ण कार्यकारी और रक्षा शक्तियां होती हैं। साथ ही, वहाँ एक प्रधानमंत्री भी होता है जो मंत्रिमंडल का नेतृत्व करता है और सरकार के दैनिक कामकाज के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। यह व्यवस्था दोहरी कार्यपालिका की विशेषता रखती है, जहाँ शासन की बागडोर राष्ट्रपति और विधायी बहुमत के बीच के राजनीतिक तालमेल पर निर्भर करती है।

291. (C) राजनीतिक विश्वासों और मूल्यों का अर्जन।
राजनीतिक समाजीकरण वह निरंतर सामाजिक प्रक्रिया है जिसका मुख्य केंद्र यह अध्ययन करना है कि व्यक्ति किस प्रकार अपने राजनीतिक विश्वासों, मूल्यों और नागरिक पहचान को प्राप्त और विकसित करते हैं। यह प्रक्रिया केवल ज्ञान प्राप्त करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के मन में अपनी राजनीतिक व्यवस्था के प्रति वफादारी या विरोध की भावनाएं पैदा करती है। परिवार, शिक्षण संस्थान और मीडिया इस कार्य में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। यह प्रक्रिया समाज की राजनीतिक संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचाती है, जो किसी भी राजनीतिक व्यवस्था की स्थिरता और वैधता का मुख्य आधार है।

292. (D) उत्पादन की विधि
मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अनुसार, मानव इतिहास का विकास और राजनीतिक प्रणालियों का स्वरूप मुख्य रूप से 'उत्पादन की विधि' द्वारा निर्धारित होता है। इसमें समाज की आर्थिक शक्तियाँ और उत्पादन के संबंध शामिल होते हैं। मार्क्स का तर्क था कि जिस वर्ग का उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण होता है, वही राजनीति, कानून और विचारधारा को भी अपने हितों के अनुसार आकार देता है। अतः, समाज में होने वाले सभी राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन अंततः आर्थिक आधार में होने वाले क्रांतिकारी बदलावों का ही प्रतिबिंब होते हैं, जो इतिहास को परिभाषित करते हैं।

293. (C) यह आदर्शात्मक और वर्णनात्मक था।
तुलनात्मक राजनीति के पारंपरिक दृष्टिकोण की परिभाषित विशेषता इसकी आदर्शात्मक और वर्णनात्मक प्रकृति है। यह दृष्टिकोण मुख्य रूप से सरकारी संस्थानों, जैसे संविधान, विधायिका और कार्यपालिका की औपचारिक-कानूनी संरचनाओं के विस्तृत विवरण तक सीमित था। इसमें विद्वान अक्सर इस बात पर चर्चा करते थे कि आदर्श राज्य या सर्वोत्तम सरकार को कैसा होना चाहिए, जो दार्शनिक चिंतन पर आधारित था। इसने राजनीतिक अभिनेताओं के वास्तविक व्यवहार और मात्रात्मक डेटा के वैज्ञानिक विश्लेषण की उपेक्षा की थी, जिसके कारण इसे बाद में आधुनिक व्यवहारवादी दृष्टिकोण द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

294. (B) समय के साथ अस्तित्व बनाए रखा जा सके।
डेविड ईस्टन के व्यवस्था विश्लेषण में एक केंद्रीय विचार यह है कि राजनीतिक व्यवस्था निरंतर तनाव और पर्यावरण के दबावों का सामना करती है। व्यवस्था का मुख्य लक्ष्य इन चुनौतियों के प्रति प्रतिक्रिया देना और उन्हें आधिकारिक निर्णयों में बदलकर अपना संतुलन बनाए रखना है। यह तनाव और संघर्ष व्यवस्था को क्रियाशील रखते हैं और उसे बदलने के लिए प्रेरित करते हैं ताकि वह पूरी तरह चरमरा न जाए। व्यवस्था का अंतिम उद्देश्य अस्तित्व बनाए रखना है। अतः, व्यवस्था द्वारा तनाव का प्रबंधन ही यह सुनिश्चित करता है कि वह बदलते सामाजिक और आर्थिक परिवेश के बावजूद क्रियाशील बनी रहे।

295. (A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।
न्यायिक समीक्षा की शक्ति किसी भी शासन व्यवस्था में विधि के शासन को सुदृढ़ करने के लिए एक अनिवार्य पहचान मानी जाती है। यह शक्ति न्यायपालिका को वह सर्वोच्च अधिकार प्रदान करती है जिसके माध्यम से वह विधायिका द्वारा पारित कानूनों और कार्यपालिका के प्रशासनिक कार्यों की संवैधानिक वैधता की जाँच कर सकती है। यदि कोई भी सरकारी कार्य संविधान की मूल भावना या प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो अदालतें उसे रद्द कर सकती हैं। यह तंत्र शक्तियों के संतुलन को बनाए रखने और नागरिकों के मौलिक अधिकारों को सत्ता की मनमानी से सुरक्षित रखने के लिए एक अनिवार्य सुरक्षा कवच है।

296. (A) व्यवस्थागत संकट
लुसियन पाई ने राजनीतिक विकास को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में वर्णित किया जिसमें राजनीतिक व्यवस्था को कई मूलभूत व्यवस्थागत संकटों का सामना करना पड़ता है और उन्हें हल करना होता है। इनमें पहचान, वैधता, पैठ, भागीदारी और वितरण के संकट शामिल हैं। पाई का तर्क था कि विकास का अर्थ व्यवस्था की वह क्षमता है जिसके माध्यम से वह इन चुनौतियों का सामना करती है और नए सामाजिक-राजनीतिक दबावों के अनुसार खुद को अनुकूलित करती है। इन संकटों का सफल समाधान ही किसी पारंपरिक समाज को एक आधुनिक, एकीकृत और कुशल राष्ट्र-राज्य में बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

297. (C) एक राष्ट्रपति द्वारा दूरदर्शन पर प्रसारित राष्ट्रीय संबोधन।
राजनीतिक संचार वह महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें राजनीतिक जानकारी और संदेशों का प्रवाह शासन और जनता के बीच होता है। एक राष्ट्रपति द्वारा दूरदर्शन पर प्रसारित राष्ट्रीय संबोधन इसका सबसे सटीक उदाहरण है, क्योंकि इसके माध्यम से सरकार अपनी नीतियों, निर्णयों और भविष्य की दिशा के बारे में सीधे नागरिकों को सूचित करती है। यह न केवल सूचना का प्रेषण है, बल्कि यह जनमत को प्रभावित करने और राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर आम सहमति बनाने का एक शक्तिशाली माध्यम भी है। आधुनिक लोकतंत्र में ऐसा संचार शासन की पारदर्शिता को सुदृढ़ करने के लिए अनिवार्य माना जाता है।

Click Here to Buy book on Amazon

298. (A) 'शासक वर्ग' की अपरिहार्यता।
गेटानो मोस्का का अभिजन सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण योगदान उनका 'शासक वर्ग' की अपरिहार्यता का विश्लेषण था। उन्होंने अपनी पुस्तक 'द रूलिंग क्लास' में तर्क दिया कि प्रत्येक समाज में शक्ति हमेशा दो वर्गों में विभाजित रहती है: एक अल्पसंख्यक वर्ग जो संगठित है और शासन करता है, और एक बहुसंख्यक वर्ग जिस पर शासन किया जाता है। मोस्का का मानना था कि अल्पसंख्यक का शासन एक सार्वभौमिक नियम है जो इसलिए संभव होता है क्योंकि शासक वर्ग संगठित होता है और एक 'राजनीतिक सूत्र' के माध्यम से अपनी सत्ता को वैध बनाता है। यह विचार आज भी शक्ति संरचनाओं के अध्ययन का आधार है।

299. (D) सरकार का दैनिक कामकाज चलाना।
तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य में, सरकार के प्रमुख का पद अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि वह राज्य के वास्तविक कार्यकारी अधिकारों का प्रयोग करता है। उनका प्राथमिक उत्तरदायित्व देश का दैनिक शासन और प्रशासन चलाना, मंत्रिमंडल का नेतृत्व करना और सरकारी नीतियों को लागू करना होता है। संसदीय प्रणाली में यह भूमिका प्रधानमंत्री निभाता है, जबकि राष्ट्राध्यक्ष अक्सर केवल औपचारिक और प्रतीकात्मक कार्य करते हैं। सरकार का प्रमुख शासन की प्रभावशीलता और निर्णयों के क्रियान्वयन के लिए सीधे तौर पर उत्तरदायी होता है, जिससे वह राजनीतिक व्यवस्था का मुख्य नीति-निर्माता और नियंत्रक बन जाता है।

300. (B) व्यवहारवादी क्रांति
तुलनात्मक राजनीति में 20वीं सदी के मध्य में आई 'व्यवहारवादी क्रांति' ने इसके अध्ययन की दिशा को पूरी तरह बदल दिया। इस आंदोलन ने आदर्शात्मक चर्चाओं से ध्यान हटाकर आनुभविक विश्लेषण पर केंद्रित किया। व्यवहारवाद ने राजनीतिक अभिनेताओं के वास्तविक और अवलोकन योग्य व्यवहार, उनके निर्णयों और उन व्यवहारों के पीछे के कारणों के अध्ययन पर जोर दिया। वैज्ञानिक पद्धतियों, डेटा संग्रह और सांख्यिकीय उपकरणों का उपयोग करते हुए, इसका उद्देश्य राजनीति के ऐसे यथार्थवादी सिद्धांतों का निर्माण करना था जिनका परीक्षण तथ्यों के आधार पर किया जा सके, जिससे यह विषय अधिक वस्तुनिष्ठ और वैज्ञानिक बन गया।

NODIA

अध्याय 04
भारतीय शासन एवं राजनीति

NODIA

1. निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान का एक प्रमुख वैचारिक आधार माना जाता है, जो सामाजिक न्याय और असमानता को कम करने के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है?
(A) उदारवादी-व्यक्तिवादी ढांचा
(B) समाजवादी सिद्धांत
(C) अराजकतावादी विचार
(D) राजशाही परंपरा

2. भारतीय संविधान की प्रस्तावना का प्राथमिक कार्य क्या है?
(A) दस्तावेज़ के मुख्य उद्देश्यों और दर्शन की रूपरेखा तैयार करना
(B) सभी मौजूदा कानूनों की एक व्यापक और विस्तृत सूची प्रदान करना
(C) विशेष रूप से न्यायपालिका की विशिष्ट शक्तियों और कर्तव्यों को निर्दिष्ट करना
(D) राष्ट्रीय संसद के लिए विशिष्ट चुनावी प्रक्रियाओं को निर्धारित करना

3. भारतीय संविधान की प्रकृति के संबंध में सही कथन की पहचान करें।
(A) यह पूरी तरह से संघीय है और इसमें कोई एकात्मक विशेषता नहीं है।
(B) यह एक कठोर संविधान है जिसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है।
(C) यह सरकार के संसदीय स्वरूप की स्थापना करता है।
(D) यह केवल केंद्रीय स्तर पर द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान करता है।

4. भारतीय संविधान में 'राज्य के नीति निदेशक तत्वों' की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है?
(A) संयुक्त राज्य अमेरिका
(B) यूनाइटेड किंगडम
(C) कनाडा
(D) आयरलैंड

5. निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकार नहीं है?
(A) समानता का अधिकार
(B) शोषण के विरुद्ध अधिकार
(C) संपत्ति का अधिकार
(D) धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार

6. निम्नलिखित सूचियों का मिलान करें और सही विकल्प चुनें।
सूची I: (संवैधानिक प्रावधान)
P. मौलिक अधिकार
Q. संसदीय प्रणाली
R. राज्य के नीति निदेशक तत्व
S. संघीय योजना
सूची II: (स्रोत संविधान)
1. आयरलैंड
2. यूनाइटेड किंगडम
3. संयुक्त राज्य अमेरिका
4. कनाडा
(A) P-3, Q-2, R-1, S-4
(B) P-1, Q-3, R-4, S-2
(C) P-3, Q-4, R-2, S-1
(D) P-2, Q-1, R-3, S-4

7. मौलिक कर्तव्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
I. इन्हें 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा जोड़ा गया था।
II. ये न्यायोचित हैं और इन्हें न्यायालयों द्वारा लागू किया जा सकता है।
III. ये केवल भारतीय नागरिकों पर लागू होते हैं।
उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) केवल I
(B) केवल I और III
(C) केवल II और III
(D) I, II और III

8. एक व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार और हिरासत में लिया जाता है। कौन सा मौलिक अधिकार उसे 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने की अनुमति देता है?
(A) संवैधानिक उपचारों का अधिकार
(B) समानता के संरक्षण का अधिकार
(C) व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार
(D) शोषण के विरुद्ध अधिकार

9. निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें।
कथन I: भारतीय संविधान को अक्सर एक 'जीवंत दस्तावेज' के रूप में वर्णित किया जाता है।
कथन II: संविधान बदलती जरूरतों और परिस्थितियों के अनुकूल होने के लिए संशोधन की प्रक्रिया प्रदान करता है।
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।

(D) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।

10. निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन शामिल हैं - अभिकथन (A) और कारण (R)। उचित विकल्प का चयन करके प्रश्न का उत्तर दें।
अभिकथन (A): भारतीय संविधान की प्रस्तावना न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है।
कारण (R): प्रस्तावना उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और बढ़ावा देना चाहता है, और यह संविधान की कानूनी व्याख्या में सहायता करती है जहां भाषा संदिग्ध पाई जाती है।
(A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(D) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

11. भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 'शिक्षा के अधिकार' से संबंधित है?
(A) अनुच्छेद 19
(B) अनुच्छेद 29
(C) अनुच्छेद 32
(D) अनुच्छेद 21A

12. सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन के साधन के रूप में संविधान का उपयोग करने की अवधारणा इसके किस भाग में सबसे प्रमुखता से परिलक्षित होती है?
(A) आपातकाल से संबंधित प्रावधान
(B) प्रस्तावना और राज्य के नीति निदेशक तत्व
(C) संघ कार्यपालिका की संरचना
(D) अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित अनुच्छेद

13. किस संवैधानिक संशोधन को उसके द्वारा किए गए बड़ी संख्या में परिवर्तनों के कारण अक्सर 'लघु-संविधान' कहा जाता है?
(A) 24वां संशोधन
(B) 44वां संशोधन
(C) 42वां संशोधन
(D) 73वां संशोधन

14. भारत में संवैधानिक संशोधनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
I. संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है।
II. राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए संशोधन विधेयक को वापस कर सकते हैं।
III. कुछ संशोधनों के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है।
उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) केवल I और II
(B) केवल II और III
(C) केवल I और III
(D) I, II और III

15. भारतीय संदर्भ में 'न्यायिक पुनरावलोकन' का क्या अर्थ है?
(A) विधायी अधिनियमों और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच करना
(B) न्यायपालिका का अपने स्वयं के पिछले निर्णयों की समीक्षा करने और उन्हें संशोधित करने का अधिकार
(C) न्यायपालिका के सामान्य कामकाज की समीक्षा करने की संसद की शक्ति
(D) संसद द्वारा पहले ही पारित कानूनों की समीक्षा करने की राष्ट्रपति की शक्ति

16. भारतीय संविधान के निर्माण की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें:
1. उद्देश्य प्रस्ताव को अपनाना
2. संविधान सभा की पहली बैठक
3. प्रारूप समिति की नियुक्ति
4. संविधान पर अंतिम हस्ताक्षर
निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रमिक क्रम का प्रतिनिधित्व करता है?
(A) 1, 2, 3, 4
(B) 2, 1, 3, 4
(C) 2, 3, 1, 4
(D) 3, 2, 1, 4

17. संविधान के वैचारिक आधारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत युग्म है?
(A) गांधीवादी सिद्धांत - कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना
(B) नेहरूवादी सिद्धांत - राज्य का उन्मूलन
(C) समाजवादी सिद्धांत - समान कार्य के लिए समान वेतन
(D) उदारवादी-बौद्धिक सिद्धांत - समान नागरिक संहिता

18. भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें शामिल होते हैं:
(A) संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य
(B) लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, जिनमें मनोनीत सदस्य भी शामिल हैं
(C) राज्यों की भागीदारी के बिना केवल लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य
(D) संसद के सभी सदस्य और प्रत्येक राज्य विधानसभा के सभी सदस्य

19. निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें।
कथन I: भारतीय संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है।
कथन II: मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।

Downloaded from www.pdf.tube

(D) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।

20. भारत के राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति एक है:
(A) कार्यकारी शक्ति
(B) न्यायिक शक्ति
(C) वित्तीय शक्ति
(D) विधायी शक्ति

21. निम्नलिखित सूचियों का मिलान करें और सही विकल्प चुनें।
सूची I: (संसदीय शब्दावली)
P. गणपूर्ति
Q. सत्रावसान
R. स्थगन
S. गिलोटिन
सूची II: (अर्थ)
1. एक निश्चित समय के लिए बैठक के कार्य को निलंबित करना
2. राष्ट्रपति द्वारा सदन के सत्र की समाप्ति
3. उपस्थित होने के लिए आवश्यक सदस्यों की न्यूनतम संख्या
4. अनुदान की सभी शेष मांगों को एक साथ मतदान के लिए रखना
(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-3, Q-2, R-1, S-4
(C) P-3, Q-1, R-2, S-4
(D) P-4, Q-3, R-1, S-2

22. भारतीय संसदीय प्रणाली के कामकाज का सबसे उपयुक्त विवरण क्या है?
(A) कार्यपालिका और विधायिका के बीच शक्तियों के पूर्ण पृथक्करण वाली प्रणाली।
(B) कार्यपालिका और विधायी शक्तियों के समन्वय और संलयन की विशेषता वाली प्रणाली।
(C) एक ऐसी प्रणाली जहाँ राष्ट्रपति सरकार का प्रमुख होता है।
(D) एक ऐसी प्रणाली जहाँ न्यायपालिका सीधे कार्यपालिका को नियंत्रित करती है।

23. संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है?
(A) भारत के राष्ट्रपति
(B) भारत के प्रधानमंत्री
(C) राज्यसभा के सभापति
(D) लोकसभा के अध्यक्ष

24. निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की एकात्मक या गैर-संघीय विशेषता माना जाता है?
(A) एकल नागरिकता
(B) लिखित संविधान
(C) शक्तियों का विभाजन
(D) स्वतंत्र न्यायपालिका

25. भारत में केंद्र-राज्य संबंधों के संदर्भ में 'स्वायत्तता' की मांग आमतौर पर किसको संदर्भित करती है?
(A) भारतीय संघ से पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग
(B) राज्यों के भीतर सरकार के राष्ट्रपति स्वरूप की मांग
(C) राज्यों के लिए अधिक शक्तियों और वित्तीय संसाधनों की मांग
(D) सभी राज्य विधान परिषदों के पूर्ण उन्मूलन की मांग

26. निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन शामिल हैं - अभिकथन (A) और कारण (R)। उचित विकल्प का चयन करके प्रश्न का उत्तर दें।
अभिकथन (A): भारतीय संघवाद को अक्सर 'अर्ध-संघीय' या 'सुदृढ़ केंद्रीकरण प्रवृत्ति वाला संघवाद' कहा जाता है।
कारण (R): भारत का संविधान एकल नागरिकता और एकीकृत न्यायपालिका का प्रावधान करता है, और कई मामलों में केंद्र सरकार के पास सर्वोपरि शक्तियां हैं।
(A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(D) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

NODIA

27. सरकारिया आयोग की नियुक्ति निम्नलिखित में से किस विषय पर प्रतिवेदन देने के लिए की गई थी?
(A) चुनावी सुधार
(B) केंद्र-राज्य संबंध
(C) न्यायिक सुधार
(D) पुलिस सुधार

28. निम्नलिखित में से कौन भारत के राजनीतिक इतिहास में एक मान्यता प्राप्त अलगाववादी आंदोलन नहीं है?
(A) पंजाब में खालिस्तान आंदोलन
(B) मध्य भारत में नर्मदा बचाओ आंदोलन
(C) दक्षिण में द्रविड़ नाडु आंदोलन
(D) नगालैंड में अलगाववादी आंदोलन

29. केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय करने की भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति इसके किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती है?
(A) सलाहकार क्षेत्राधिकार
(B) अपीलीय क्षेत्राधिकार
(C) मूल क्षेत्राधिकार
(D) रिट क्षेत्राधिकार

30. भारत में न्यायिक सक्रियता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
I. यह नागरिकों के अधिकारों के संरक्षण में न्यायपालिका द्वारा निभाई गई सक्रिय भूमिका को संदर्भित करता है।
II. जनहित याचिका न्यायिक सक्रियता का एक महत्वपूर्ण परिणाम है।
III. कभी-कभी विधायिका और कार्यपालिका के क्षेत्रों में अतिक्रमण करने के लिए इसकी आलोचना की जाती है।

282. (A) जनता का प्रतिनिधित्व करना और कानून बनाना
तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य में, विधायिका किसी भी लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था का वह सर्वोच्च अंग है जिसका प्राथमिक उत्तरदायित्व जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व करना और समाज के लिए कानूनों का निर्माण करना है। यह एक ऐसा मंच है जहाँ विभिन्न हितों और दृष्टिकोणों पर बहस की जाती है और सार्वजनिक नीतियों को औपचारिक रूप दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, विधायिका बजट पर नियंत्रण रखती है और कार्यकारी शाखा की गतिविधियों की निगरानी सुनिश्चित करती है। यह शासन को जवाबदेह बनाए रखने और नागरिकों की आकांक्षाओं को नीतिगत रूप देने के लिए अनिवार्य संस्था है।

283. (D) 1, 2 और 3
राजनीतिक विकास की अवधारणा अत्यंत व्यापक है जिसमें व्यवस्था की समस्याओं को हल करने की क्षमता में वृद्धि और भूमिकाओं का संरचनात्मक विभेदीकरण शामिल है। लुसियन पाई जैसे विद्वानों ने इसे समानता, क्षमता और विभेदीकरण के त्रि-स्तरीय लक्षणों से जोड़ा है। शुरुआती सिद्धांतों में अक्सर विकास को पश्चिमीकरण के समान माना गया था, जिसे बाद में आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। आधुनिक दृष्टिकोण यह मानता है कि विकास का अर्थ संस्थागत सुदृढ़ीकरण और बदलती सामाजिक-आर्थिक मांगों के साथ तालमेल बिठाने की शक्ति प्राप्त करना है, जिससे राजनीतिक व्यवस्था अधिक स्थिर और प्रभावी बन सके।

284. (B) राजनीतिक संचार
जनसंचार माध्यम राजनीतिक संचार की प्रक्रिया के अनिवार्य और सबसे शक्तिशाली घटक हैं। वे सरकार और जनता के बीच सूचनाओं के आदान-प्रदान के मुख्य सेतु के रूप में कार्य करते हैं। मीडिया न केवल सरकारी निर्णयों और नीतियों को जनता तक पहुँचाता है, बल्कि जनमत और सामाजिक चिंताओं को भी शासन के सामने प्रस्तुत करता है। यह सूचना का प्रवाह नागरिकों को जागरूक बनाता है और शासन की पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। अतः, प्रभावी राजनीतिक संचार व्यवस्था के बिना लोकतंत्र में लोकमत का निर्माण और जवाबदेही संभव नहीं है, जो इसकी महत्ता को दर्शाता है।

285. (C) एक वर्ग जो शासन करता है और एक वर्ग जिस पर शासन किया जाता है।
गेटानो मोस्का ने अपने 'शासक वर्ग' के सिद्धांत में यह तर्क दिया कि प्रत्येक समाज में, चाहे वह किसी भी काल या व्यवस्था का हो, शक्ति हमेशा दो मुख्य वर्गों में विभाजित रहती है। एक अल्पसंख्यक वर्ग जो संगठित है और शासन करता है, और एक बहुसंख्यक वर्ग जिस पर शासन किया जाता है। मोस्का के अनुसार, शासक वर्ग अपनी बेहतर संगठनात्मक क्षमता और भौतिक संसाधनों के कारण सत्ता पर अपना नियंत्रण बनाए रखता है। यह वर्ग अपने शासन को वैध बनाने के लिए एक 'राजनीतिक सूत्र' का उपयोग करता है, जिससे जनसमूह उसकी सत्ता को स्वीकार करता है।

286. (D) नौकरशाही - हित समूहन
राजनीतिक व्यवस्था के कार्यों और संस्थानों के बीच का मिलान यह स्पष्ट करता है कि विधायिका नियम बनाती है, कार्यपालिका उन्हें लागू करती है और न्यायपालिका उनका अधिनिर्णयन करती है। 'हित समूहन' का कार्य मुख्य रूप से 'राजनीतिक दलों' द्वारा किया जाता है, न कि नौकरशाही द्वारा। नौकरशाही मुख्य रूप से नियम अनुप्रयोग और प्रशासन के कार्यों के लिए उत्तरदायी है। हित समूहन की प्रक्रिया में विभिन्न सामाजिक मांगों को एकीकृत करके सुसंगत नीतिगत विकल्पों में बदला जाता है, जो राजनीतिक नेतृत्व और दलों का कार्य है। अतः, नौकरशाही और हित समूहन का युग्म गलत है।

287. (A) यह समझना कि विभिन्न संरचनाएं समान कार्य कैसे निष्पादित करती हैं।
संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग यह है कि यह विद्वानों को यह समझने में मदद करता है कि विभिन्न राजनीतिक प्रणालियाँ, अपनी विविध संस्थागत संरचनाओं के बावजूद, समाज के लिए आवश्यक प्रकार्यों को कैसे पूरा करती हैं। यह दृष्टिकोण उन सार्वभौमिक कार्यों—जैसे हित प्रकटीकरण और नियम निर्माण—पर ध्यान केंद्रित करता है जो सभी व्यवस्थाओं को जीवित रखने के लिए अनिवार्य हैं। इससे हमें एक आधुनिक लोकतंत्र और एक पारंपरिक समाज के बीच तुलना करने का एक वैज्ञानिक आधार मिलता है, जो केवल औपचारिक-कानूनी विवरणों तक सीमित रहने के बजाय वास्तविक राजनीतिक प्रक्रियाओं का विश्लेषण करता है।

288. (A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं और कथन II, कथन I की सही व्याख्या है।
अभिजनवादी सिद्धांत शास्त्रीय लोकतंत्र की इस पारंपरिक धारणा की कड़ी आलोचना करता है कि शक्ति वास्तव में जनता के हाथों में होती है। इस सिद्धांत का मुख्य तर्क यह है कि आधुनिक समाज की जटिलता और विशालता के कारण निर्णय लेने की वास्तविक शक्ति अनिवार्य रूप से एक छोटे, संगठित और सक्षम अल्पसंख्यक के पास ही रहती है। जनता स्वयं शासन नहीं कर सकती, बल्कि वह केवल प्रतिस्पर्धी अभिजनों के बीच चुनाव करती है। अतः, 'जनता का शासन' एक व्यावहारिक मिथक है, क्योंकि किसी भी बड़े समाज में सत्ता का वास्तविक प्रयोग हमेशा कुछ चुने हुए लोगों द्वारा ही किया जाता है।

289. (B) राज्यों के बीच राजनयिक संवाद
तुलनात्मक राजनीति का दायरा मुख्य रूप से राष्ट्रों के भीतर की राजनीतिक गतिविधियों तक सीमित है, जिसमें औपचारिक संस्थान, अनौपचारिक प्रक्रियाएं और सार्वजनिक नीतियों का विश्लेषण शामिल है। राज्यों के बीच राजनयिक संवाद, युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय संगठन अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन का प्राथमिक विषय हैं। तुलनात्मक राजनीति यह समझने का प्रयास करती है कि आंतरिक घरेलू परिस्थितियां शासन को कैसे प्रभावित करती हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध संप्रभु राज्यों के बीच के बाहरी अंतर्संबंधों और वैश्विक व्यवस्था की राजनीति पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो इसे भिन्न बनाता है।

Click Here to Buy book on Amazon

बदलते रुझान

41. दल-बदल विरोधी कानून किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के माध्यम से लागू किया गया था?
(A) 42वां संशोधन अधिनियम
(B) 44वां संशोधन अधिनियम
(C) 52वां संशोधन अधिनियम
(D) 61वां संशोधन अधिनियम

42. निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन शामिल हैं - अभिकथन (A) और कारण (R)। उचित विकल्प का चयन करके प्रश्न का उत्तर दें।
अभिकथन (A): भारतीय राजनीति और चुनावी व्यवहार में जाति एक महत्वपूर्ण कारक बनी हुई है।
कारण (R): राजनीतिक दल अक्सर चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन करते समय जातिगत समीकरणों पर विचार करते हैं।
(A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(D) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

43. "मंडल आयोग" का गठन निम्नलिखित में से किस मुद्दे के अध्ययन के लिए किया गया था?
(A) केंद्र-राज्य प्रशासनिक संबंधों में सुधार
(B) व्यापक चुनावी सुधारों को लागू करना
(C) राष्ट्रीय एकीकरण की समस्याओं का विश्लेषण करना
(D) सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति

44. निम्नलिखित में से कौन भारत में राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या नहीं है?
(A) सांप्रदायिकता
(B) संघवाद
(C) क्षेत्रवाद
(D) जातिवाद

45. भारत में 'दलित' राजनीति की अवधारणा मुख्य रूप से किससे जुड़ी है?
(A) उदारीकरण की राजनीतिक और आर्थिक नीतियां
(B) नए क्षेत्रीय राज्यों के निर्माण का आंदोलन
(C) अनुसूचित जातियों द्वारा पहचान का दावा और सामाजिक न्याय की मांग
(D) गुटनिरपेक्षता पर आधारित ऐतिहासिक विदेश नीति

46. अनुच्छेद 32 के तहत 'संवैधानिक उपचारों के अधिकार' का मुख्य उद्देश्य क्या है?
(A) संपत्ति का मौलिक अधिकार प्रदान करना
(B) संविधान में संशोधन की प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार करना
(C) राष्ट्रपति को क्षमादान शक्तियां प्रदान करना
(D) सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन को सुनिश्चित करना

47. संविधान पर राष्ट्रीय आंदोलन के प्रभाव से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
I. सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार लोकतंत्र के प्रति राष्ट्रीय आंदोलन की प्रतिबद्धता का परिणाम था।
II. नेहरू रिपोर्ट (1928) ने अधिकारों के घोषणापत्र का प्रस्ताव दिया था।
III. राष्ट्रवादी नेता सरकार के संसदीय स्वरूप के विरुद्ध थे।
उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) केवल III
(B) केवल I और II
(C) केवल II और III
(D) I, II और III

48. संविधान के माध्यम से 'सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन' का तात्पर्य है:
(A) मौजूदा सामाजिक व्यवस्था को हिंसक रूप से उखाड़ फेंकना
(B) संवैधानिक साधनों का उपयोग करते हुए एक समतावादी समाज की ओर शांतिपूर्ण परिवर्तन
(C) अर्थव्यवस्था के पूंजीवादी मॉडल को तीव्र गति से अपनाना
(D) बिना किसी सामाजिक विचार के केवल आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करना

49. निम्नलिखित में से किस संवैधानिक विकास ने पहली बार ब्रिटिश भारत में मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल के सिद्धांत की शुरुआत की थी?
(A) 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम
(B) 1909 के मार्ले-मिंटो सुधार
(C) 1919 के मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार
(D) 1935 का भारत सरकार अधिनियम

50. भारत के राष्ट्रपति के बारे में एक गलत कथन की पहचान करें।
(A) राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं।
(B) राष्ट्रपति रक्षा बलों के सर्वोच्च सेनापति होते हैं।
(C) संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है।
(D) राष्ट्रपति प्रत्येक आम चुनाव के बाद संसद के पहले सत्र को संबोधित करते हैं।

NODIA

51. भारत में संसदीय प्रणाली का कामकाज किस सिद्धांत पर आधारित है?
(A) सत्ता का संकेंद्रण
(B) न्यायिक सर्वोच्चता
(C) सामूहिक उत्तरदायित्व
(D) राष्ट्रपति का विवेक

52. भारतीय संसदीय संदर्भ में 'द्विसदनीयता' शब्द का अर्थ है:
(A) दो प्रमुख राजनीतिक दलों की उपस्थिति।

(B) सरकार का दो स्तरों, संघ और राज्य में विभाजन।
(C) संसद सदस्यों के लिए दो साल का कार्यकाल।
(D) विधायिका के दो सदनों का अस्तित्व।

53. यदि भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहते हैं, तो उन्हें अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करना चाहिए?
(A) प्रधानमंत्री को
(B) भारत के मुख्य न्यायाधीश को
(C) भारत के उपराष्ट्रपति को
(D) लोकसभा अध्यक्ष को

54. सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित ऐतिहासिक मामलों पर विचार करें:
1. केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य
2. ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य
3. मेनका गांधी बनाम भारत संघ
4. गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य

निम्नलिखित में से कौन सा उनके निर्णय का सही कालानुक्रमिक क्रम दर्शाता है?
(A) 1, 2, 4, 3
(B) 2, 4, 1, 3
(C) 2, 1, 4, 3
(D) 4, 2, 1, 3

55. निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें।
कथन I: 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियमों का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर संघवाद को सुदृढ़ करना था।
कथन II: इन संशोधनों ने पंचायती राज और शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया।
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
(D) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।

56. राज्य की स्वायत्तता की मांग और अलगाववादी आंदोलनों में मुख्य रूप से क्या अंतर है?
(A) स्वायत्तता संवैधानिक ढांचे के भीतर कार्य करती है, जबकि अलगाववाद पृथक होने का प्रयास करता है
(B) स्वायत्तता की मांगें सदैव हिंसक होती हैं, जबकि अलगाववादी आंदोलन निरंतर शांतिपूर्ण होते हैं
(C) स्वायत्तता की मांगें पूर्णतः आर्थिक हैं, जबकि अलगाववादी आंदोलन पूर्णतः राजनीतिक हैं
(D) स्वायत्तता की मांग दलों द्वारा की जाती है, जबकि अलगाववादी आंदोलनों का नेतृत्व व्यक्तियों द्वारा किया जाता है

57. भारत में 'न्यायिक सुधारों' की अवधारणा में आम तौर पर निम्नलिखित को छोड़कर सभी शामिल हैं:
(A) न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाना।
(B) मामलों के लंबित रहने को समाप्त करने के लिए द्रुतगामी न्यायालयों की स्थापना करना।
(C) न्यायिक पुनरावलोकन की शक्तियों को कम करना।
(D) वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र को बढ़ावा देना।

58. निम्नलिखित में से कौन सा एक 'प्रचारक' दबाव समूह का सबसे अच्छा उदाहरण है?
(A) वन्यजीवों के संरक्षण के लिए अभियान चलाने वाला एक पर्यावरण समूह
(B) अपने पंजीकृत सदस्यों के लिए बेहतर वेतन के लिए संघर्ष करने वाला एक श्रमिक संघ
(C) राष्ट्रीय स्तर पर कम निगम करों के लिए पैरवी करने वाला एक व्यापार संघ
(D) अपने समुदाय के लिए आरक्षण की मांग करने वाला एक जाति-आधारित संघ

59. लोकसभा चुनावों में उपयोग की जाने वाली 'सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय' चुनावी प्रणाली का अर्थ है कि जीतने वाला उम्मीदवार वह है जो:
(A) डाले गए कुल मतों का 50% से अधिक प्राप्त करता है।
(B) एक निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है।
(C) कम से कम आधे मतदान केंद्रों में बहुमत प्राप्त करता है।
(D) अन्य सभी उम्मीदवारों की तुलना में सबसे अधिक मत प्राप्त करता है।

60. निम्नलिखित सूचियों का मिलान करें और सही विकल्प चुनें।
सूची I: (समिति)
P. बलवंत राय मेहता समिति
Q. सरकारिया आयोग
R. तारकुंडे समिति
S. मंडल आयोग
सूची II: (विषय वस्तु)
1. केंद्र-राज्य संबंध
2. अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण
3. पंचायती राज
4. चुनावी सुधार
(A) P-3, Q-1, R-4, S-2
(B) P-1, Q-3, R-4, S-2
(C) P-3, Q-2, R-1, S-4
(D) P-2, Q-4, R-3, S-1

61. भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य शामिल हैं?
(A) भाग III
(B) भाग IV
(C) भाग IV-A
(D) भाग V

62. अनुच्छेद 368 के तहत संवैधानिक संशोधन की शक्ति निम्नलिखित में संशोधन करने तक विस्तृत नहीं है:
(A) मौलिक अधिकार।
(B) प्रस्तावना।
(C) राज्य के नीति निदेशक तत्व।
(D) संविधान का मूल ढांचा।

Downloaded from www.pdf.tube

63. निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन शामिल हैं - अभिकथन (A) और कारण (R)। उचित विकल्प का चयन करके प्रश्न का उत्तर दें।
अभिकथन (A): मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से एक इकाई के रूप में कार्य करती है।
कारण (R): मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, और किसी एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव संपूर्ण परिषद के खिलाफ प्रस्ताव माना जाता है।
(A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(D) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

64. यदि संसद के किसी गैर-सदस्य को मंत्री नियुक्त किया जाता है तो क्या प्रावधान है?
(A) वे संसद की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकते।
(B) उन्हें छह महीने के भीतर संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना होगा।
(C) वे संसद का सदस्य बने बिना अनिश्चित काल तक मंत्री बने रह सकते हैं।
(D) वे केवल राज्य मंत्री हो सकते हैं, कैबिनेट मंत्री नहीं।

65. संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का वितरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है?
(A) चौथी अनुसूची
(B) सातवीं अनुसूची
(C) छठी अनुसूची
(D) दसवीं अनुसूची

66. भारत के सर्वोच्च न्यायालय के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
I. यह भारत में अपील का सर्वोच्च न्यायालय है।
II. इसके पास न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है।
III. इसका मूल क्षेत्राधिकार अनन्य है।
उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) केवल I और II
(B) केवल II और III
(C) केवल I और III
(D) I, II और III

67. निम्नलिखित में से कौन सी भारत सरकार अधिनियम, 1935 की विशेषता नहीं है?
(A) अखिल भारतीय संघ
(B) केंद्र में द्वैध शासन
(C) सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की शुरुआत
(D) प्रांतीय स्वायत्तता

68. भारत के लिए संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था?
(A) भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
(B) मुस्लिम लीग
(C) महात्मा गांधी
(D) एम. एन. राय

69. निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें।
कथन I: मौलिक अधिकार पूर्ण हैं और उन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है।
कथन II: राज्य लोक व्यवस्था, नैतिकता और राज्य की सुरक्षा के हित में मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है।
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।
(D) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।

70. संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करता है?
(A) अनुच्छेद 19
(B) अनुच्छेद 21
(C) अनुच्छेद 20
(D) अनुच्छेद 22

71. 1978 का 44वां संशोधन अधिनियम महत्वपूर्ण था क्योंकि इसने:
(A) प्रस्तावना में 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द जोड़ा।
(B) लोकसभा का कार्यकाल छह वर्ष तक बढ़ाया।
(C) मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा प्रस्तुत की।
(D) संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के स्थान पर विधिक अधिकार बना दिया।

NODIA

72. भारत में 'संसदीय प्रणाली के कामकाज' का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है?
(A) विधायिका के प्रति कार्यपालिका की उत्तरदायित्व।
(B) राष्ट्रपति की औपचारिक भूमिका।
(C) नागरिक सेवाओं का स्थायित्व।
(D) लोकसभा पर राज्यसभा की सर्वोच्चता।

73. भारत में विधायी 'अवशिष्ट शक्तियां' किसमें निहित हैं?
(A) राज्य विधानमंडलों में
(B) राष्ट्रपति में
(C) केंद्रीय संसद में
(D) सर्वोच्च न्यायालय में

74. एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ मामले के संदर्भ में, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से किससे संबंधित निर्देश दिए थे?
(A) अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन का दायरा।
(B) समान नागरिक संहिता का कार्यान्वयन।
(C) पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण नीति।
(D) वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा।

75. निम्नलिखित में से कौन जनमत को प्रभावित करने का औपचारिक साधन नहीं है?
(A) राजनीतिक दलों द्वारा घोषणापत्र जारी करना।
(B) सरकार द्वारा नीतिगत दस्तावेज प्रकाशित करना।
(C) मीडिया द्वारा समाचार और विश्लेषण प्रसारित करना।
(D) सोशल मीडिया के माध्यम से असत्यापित जानकारी फैलाना।

76. भारतीय राजनीति में 'वर्ग' की अवधारणा अक्सर किस अन्य प्रमुख सामाजिक विभाजन के साथ मेल खाती है?
(A) क्षेत्र
(B) जाति
(C) भाषा
(D) लिंग

77. निम्नलिखित में से कौन भारत के निर्वाचन आयोग की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है?
(A) यह बिना किसी वास्तविक शक्ति के एक सलाहकार निकाय है।
(B) यह विधि और न्याय मंत्रालय का एक अधीनस्थ विभाग है।
(C) यह चुनावी प्रक्रिया के प्रशासन के लिए उत्तरदायी एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है।
(D) यह चुनाव से संबंधित कानून बनाने के लिए उत्तरदायी है।

78. निम्नलिखित में से कौन एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल का उदाहरण है?
(A) भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
(B) भारतीय जनता पार्टी
(C) भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)
(D) द्रविड़ मुनेत्र कड़गम

79. "न्यायिक सक्रियता" शब्द का तात्पर्य है:
(A) सार्वजनिक कर्तव्यों को लागू करने और अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका द्वारा सक्रिय भूमिका निभाना।
(B) न्यायाधीशों का राजनीतिक रैलियों में सक्रिय रूप से भाग लेना।
(C) न्यायपालिका का पूर्व मिसाल के सिद्धांत का कठोरता से पालन करना।
(D) न्यायिक निर्णयों को रद्द करने की विधायिका की शक्ति।

80. गलत युग्म की पहचान करें।
(A) अनुच्छेद 17 - अस्पृश्यता का अंत
(B) अनुच्छेद 32 - संपत्ति का अधिकार
(C) अनुच्छेद 25 - धार्मिक स्वतंत्रता
(D) अनुच्छेद 51A - मौलिक कर्तव्य

81. निम्नलिखित संवैधानिक पदों पर विचार करें:
1. राष्ट्रपति
2. उपराष्ट्रपति
3. प्रधानमंत्री
4. लोकसभा अध्यक्ष

निम्नलिखित में से कौन वरीयता का सही क्रम दर्शाता है?
(A) उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष
(B) राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष
(C) राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री
(D) उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष

82. भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधन किया गया था?
(A) 42वां संशोधन अधिनियम
(B) 24वां संशोधन अधिनियम
(C) 44वां संशोधन अधिनियम
(D) इसमें कभी संशोधन नहीं किया गया है।

83. संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे?
(A) जवाहरलाल नेहरू
(B) डॉ. राजेंद्र प्रसाद
(C) डॉ. बी.आर. अंबेडकर
(D) सरदार वल्लभभाई पटेल

84. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में 'कानून के समक्ष समानता' वाक्यांश किस देश के संविधान से प्रेरित है?
(A) अमेरिका
(B) फ्रांस
(C) सोवियत संघ
(D) ब्रिटेन

85. निम्नलिखित में से कौन सा गांधीवादी विचारधारा पर आधारित राज्य का नीति निदेशक तत्व है?
(A) समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना।
(B) शैशव पूर्व देखभाल और शिक्षा प्रदान करना।
(C) ग्राम पंचायतों को स्वशासन की इकाइयों के रूप में संगठित करना।
(D) पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना।

86. निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन शामिल हैं - अभिकथन (A) और कारण (R)। उचित विकल्प का चयन करके प्रश्न का उत्तर दें।
अभिकथन (A): राज्यसभा एक स्थायी सदन है और इसका विघटन नहीं होता है।
कारण (R): इसके एक-तिहाई सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं।
(A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(D) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

87. निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव, यदि लोकसभा में पारित हो जाता है, तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ सकता है?

Click Here to Buy book on Amazon

STUDYING FROM PDFs?

THINK AGAIN.

If you are studying only from PDFs,
you are wasting valuable time.

Research shows that learning from

PRINTED BOOKS has up to

4× HIGHER RETENTION

than studying from screens.

PRINT BOOK = BETTER MEMORY

PDF = LOWER RETENTION

Those who study from **PRINTED BOOKS**
move **AHEAD.**

Others are left **BEHIND**
in competition.

In competitive exams,
being average is not enough.

STAY ONE STEP AHEAD.

(A) निंदा प्रस्ताव
(B) स्थगन प्रस्ताव
(C) ध्यानाकर्षण प्रस्ताव
(D) अविश्वास प्रस्ताव

88. हाल के दशकों में भारत में केंद्र-राज्य संबंधों में उभरती प्रवृत्ति किसकी ओर रही है?
(A) सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद।
(B) सत्ता का अधिक केंद्रीकरण।
(C) राज्य सरकारों का उन्मूलन।
(D) राज्यों की पूर्ण वित्तीय स्वतंत्रता।

89. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है?
(A) राज्य के राज्यपाल द्वारा।
(B) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा।
(C) संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा।
(D) राज्य विधायिका द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा।

90. निम्नलिखित सूचियों का मिलान करें और सही विकल्प चुनें।
सूची I: (रिट)
P. बंदी प्रत्यक्षीकरण
Q. परमादेश
R. उत्प्रेषण
S. अधिकार-पृच्छा
सूची II: (शाब्दिक अर्थ)
1. हम आदेश देते हैं
2. किस अधिकार से
3. सदेह प्रस्तुत करना
4. पूर्णतया सूचित होना
(A) P-3, Q-1, R-4, S-2
(B) P-1, Q-3, R-2, S-4
(C) P-3, Q-2, R-1, S-4
(D) P-2, Q-4, R-3, S-1

91. भारतीय राजनीति में 'लिंग' का मुद्दा मुख्य रूप से किससे संबंधित है?
(A) केवल समान नागरिक संहिता से।
(B) महिलाओं के लिए मतदान का अधिकार।
(C) महिलाओं के लिए एक पृथक राज्य का निर्माण।
(D) राजनीतिक संस्थाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व।

92. भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में 'राष्ट्र-निर्माण' की समस्या में शामिल है:
(A) सभी नागरिकों पर एक ही भाषा और संस्कृति थोपना।
(B) विविधता का सम्मान करते हुए एक साझा पहचान और साझा नागरिकता को बढ़ावा देना।
(C) सभी क्षेत्रीय और सांस्कृतिक अंतरों को समाप्त करना।
(D) सामाजिक सामंजस्य की कीमत पर आर्थिक विकास को बढ़ावा देना।

93. निम्नलिखित में से कौन सा भारत में लागू किया गया एक प्रमुख चुनावी सुधार है?
(A) निर्वाचन आयोग का उन्मूलन।
(B) सभी राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगाना।
(C) इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की शुरुआत।
(D) सभी नागरिकों के लिए मतदान अनिवार्य करना।

94. निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें।
कथन I: दबाव समूह और राजनीतिक दल एक ही होते हैं।
कथन II: जहाँ राजनीतिक दलों का लक्ष्य सत्ता प्राप्त करना होता है, वहीं दबाव समूहों का लक्ष्य सत्ता में बैठे लोगों को प्रभावित करना होता है।
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।
(D) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।

95. सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन के एक उपकरण के रूप में संविधान के संदर्भ में, किस मामले ने यह स्थापित किया कि मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्व 'एक रथ के दो पहिये' हैं?
(A) मिनर्वा मिल्स मामला
(B) गोलकनाथ मामला
(C) केशवानंद भारती मामला
(D) चंपकम दोराइराजन मामला

96. प्रधानमंत्री की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
I. प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं।
II. प्रधानमंत्री मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन और फेरबदल करते हैं।
III. प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की सिफारिश कर सकते हैं।
उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) केवल II
(B) केवल I और III
(C) केवल II और III
(D) I, II और III

97. संघीय ढांचे के बावजूद, भारत में एक सुदृढ़ एकात्मक झुकाव है। निम्नलिखित में से कौन सा इस एकात्मक झुकाव की अभिव्यक्ति नहीं है?
(A) राज्यपाल का पद
(B) कानून बनाने के लिए राज्य सूचियों का अस्तित्व
(C) अखिल भारतीय सेवाएं
(D) आपातकालीन प्रावधान

98. अक्सर चर्चा में रहने वाली कॉलेजियम प्रणाली किससे संबंधित है:
(A) न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण।
(B) चुनाव का संचालन।

Downloaded from www.pdf.tube

149. "न्यायिक सक्रियता" की अवधारणा को अक्सर किस सिद्धांत के साथ संघर्ष की स्थिति में देखा जाता है?
(A) विधि का शासन
(B) शक्तियों का पृथक्करण
(C) संघवाद
(D) धर्मनिरपेक्षता

150. निम्नलिखित सूचियों का मिलान करें और सही विकल्प चुनें।
सूची I: (वैचारिक सिद्धांत)
P. समाजवादी सिद्धांत
Q. गांधीवादी सिद्धांत
R. उदारवादी-बौद्धिक सिद्धांत
S. अंतरराष्ट्रीय सिद्धांत
सूची II: (राज्य के नीति निदेशक तत्वों में प्रावधान)
1. अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना
2. समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना
3. धन के संकेंद्रण को रोकना
4. कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना
(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-3, Q-4, R-2, S-1
(C) P-3, Q-2, R-4, S-1
(D) P-4, Q-3, R-1, S-2

151. किस अधिनियम ने प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत करके संवैधानिक विकास की ओर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया?
(A) भारतीय परिषद अधिनियम, 1909
(B) भारत सरकार अधिनियम, 1919
(C) भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947
(D) भारत सरकार अधिनियम, 1935

152. भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही कथन की पहचान करें।
(A) यह संविधान के मूल दर्शन और मौलिक मूल्यों को समाहित करती है।
(B) इसे शेष संविधान के लागू होने से पहले अधिनियमित किया गया था।
(C) यह विधायिका के लिए शक्ति का एक स्रोत है।
(D) 'समाजवादी' और 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द मूल प्रस्तावना का हिस्सा थे।

153. 'प्रतिषेध' की रिट एक उच्च न्यायालय द्वारा किसके लिए जारी की जाती है:
(A) किसी अधिकारी को सार्वजनिक कर्तव्य निभाने के लिए।
(B) निचली अदालत के आदेश को रद्द करने के लिए।
(C) एक निचली अदालत को उसके क्षेत्राधिकार से बाहर जाने से रोकने के लिए।
(D) किसी सार्वजनिक पद पर दावे की वैधता की जांच करने के लिए।

154. 2002 का 86वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन की दिशा में एक प्रमुख कदम था क्योंकि इसने:
(A) शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया।
(B) राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की।
(C) निजी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान किया।
(D) राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया।

155. निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें।
कथन I: भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से पद से हटाया जा सकता है।
कथन II: राष्ट्रपति पर महाभियोग का आधार 'संविधान का उल्लंघन' है।
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
(D) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।

156. भारतीय संसद में शून्य काल क्या है:
(A) बैठक का प्रथम घंटा।
(B) प्रश्न काल के तुरंत बाद का समय।
(C) एक संवैधानिक रूप से अनिवार्य उपकरण।
(D) दिन की बैठक का अंतिम घंटा।

157. संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नए राज्य बनाने का अधिकार देता है?
(A) अनुच्छेद 1
(B) अनुच्छेद 2
(C) अनुच्छेद 3
(D) अनुच्छेद 4

NODIA

158. विधि या तथ्य के किसी भी प्रश्न पर राष्ट्रपति को सलाह देने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति इसके किस क्षेत्राधिकार का हिस्सा है?
(A) मूल क्षेत्राधिकार
(B) अपीलीय क्षेत्राधिकार
(C) समीक्षा क्षेत्राधिकार
(D) सलाहकार क्षेत्राधिकार

159. एक "सांप्रदायिक" दबाव समूह किसके हितों को बढ़ावा देना चाहता है?
(A) समाज का एक विशेष धार्मिक या जातीय वर्ग।
(B) एक विशेष व्यावसायिक क्षेत्र।
(C) एक विशिष्ट पेशेवर समूह।
(D) समग्र रूप से समाज।

160. निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन शामिल हैं - अभिकथन (A) और कारण (R)। उचित विकल्प का चयन करके प्रश्न का उत्तर दें।
अभिकथन (A): भारत का निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है।
कारण (R): स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के

(C) संविधान की व्याख्या करने की न्यायपालिका की शक्ति।
(D) सभी कानूनों की समीक्षा करने की राष्ट्रपति की शक्ति।

112. भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश प्रणाली से इस अर्थ में भिन्न है कि भारत में:
(A) राष्ट्र प्रमुख के रूप में एक सम्राट होता है।
(B) एक लिखित संविधान और न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है।
(C) एक द्विसदनीय विधायिका है।
(D) सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली है।

113. यदि किसी साधारण विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध होता है, तो गतिरोध को किसके द्वारा दूर किया जाता है?
(A) सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय से।
(B) दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से।
(C) राष्ट्रपति के सीधे हस्तक्षेप से।
(D) विधेयक स्वतः ही समाप्त हो जाता है।

114. 'दलित' शब्द को 1970 के दशक में किस राजनीतिक समूह द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था?
(A) दलित पैंथर्स
(B) द्रविड़ कड़गम
(C) बहुजन समाज पार्टी
(D) रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया

115. संविधान द्वारा परिकल्पित लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या क्या है?
(A) 500
(B) 543
(C) 552
(D) 545

116. निम्नलिखित सूचियों का मिलान करें और सही विकल्प चुनें।
सूची I: (अनुच्छेद)
P. अनुच्छेद 14
Q. अनुच्छेद 40
R. अनुच्छेद 72
S. अनुच्छेद 368
सूची II: (प्रावधान)
1. राष्ट्रपति की क्षमादान देने की शक्ति
2. संसद की संविधान में संशोधन करने की शक्ति
3. विधि के समक्ष समानता
4. ग्राम पंचायतों का संगठन
(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-3, Q-4, R-2, S-1
(C) P-3, Q-4, R-1, S-2
(D) P-4, Q-3, R-1, S-2

117. संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है?
(A) दूसरी अनुसूची
(B) तीसरी अनुसूची
(C) चौथी अनुसूची
(D) पांचवीं अनुसूची

118. निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 51A के तहत मौलिक कर्तव्य नहीं है?
(A) संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों का सम्मान करना।
(B) नियमित रूप से करों का भुगतान करना।
(C) सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना।
(D) प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना।

119. दबाव समूह की एक परिभाषित विशेषता जो इसे सामाजिक आंदोलन से भिन्न करती है, वह है इसकी:
(A) किसी विशेष नीतिगत मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करना।
(B) विरोध और प्रदर्शनों का उपयोग।
(C) राजनीतिक सत्ता में रुचि की कमी।
(D) पैरवी के लिए औपचारिक संगठन और संरचना।

120. भारत के निर्वाचन आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
I. यह एक बहु-सदस्यीय निकाय है।
II. मुख्य निर्वाचन आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही पद से हटाया जा सकता है।
III. यह मतदाता सूची तैयार करने के लिए उत्तरदायी है।
उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) केवल I और II
(B) केवल II और III
(C) केवल I और III
(D) I, II और III

121. 'मूल संरचना' का सिद्धांत, जो न्यायपालिका द्वारा संवैधानिक समीक्षा का एक रूप है, पहली बार किस ऐतिहासिक मामले में स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया गया था?
(A) ए. के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य
(B) गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य
(C) केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य
(D) मेनका गांधी बनाम भारत संघ

122. 'त्रिशंकु संसद' शब्द उस स्थिति को संदर्भित करता है जहाँ:
(A) किसी भी एक दल या चुनाव पूर्व गठबंधन को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है।
(B) संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है।
(C) संसद का संयुक्त सत्र बुलाया गया होता है।
(D) संसद सदस्य हड़ताल पर चले जाते हैं।

123. मंत्रिपरिषद के प्रमुख के रूप में प्रधानमंत्री का कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है?
(A) राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करना।
(B) सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना।

Click Here to Buy book on Amazon

(D) I, II और III

173. राष्ट्रीय महिला आयोग एक है:
(A) संवैधानिक निकाय
(B) कार्यकारी निकाय
(C) वैधानिक निकाय
(D) गैर-सरकारी संगठन

174. "संविधानवाद" की अवधारणा का अर्थ है:
(A) एक लिखित संविधान का होना।
(B) शासितों की सहमति से सरकार।
(C) एक ही प्राधिकारी में निहित पूर्ण शक्ति।
(D) नियंत्रण और संतुलन के साथ सीमित सरकार।

175. निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें।
कथन I: भारतीय संविधान एक दोहरी राजव्यवस्था स्थापित करता है।
कथन II: संविधान पूरे देश के लिए एक एकल, एकीकृत न्यायिक प्रणाली प्रदान करता है।
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
(D) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।

176. निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के भीतर नहीं है?
(A) प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना।
(B) मृत्युदंड के मामले में क्षमादान देना।
(C) राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करना।
(D) संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करना।

177. भारत में उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए 'कॉलेजियम' में भारत के मुख्य न्यायाधीश और कौन शामिल होते हैं?
(A) सर्वोच्च न्यायालय के चार सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश।
(B) सर्वोच्च न्यायालय के दो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश।
(C) भारत के कानून मंत्री।
(D) भारत के राष्ट्रपति।

178. वह घटना जहाँ मतदाता संसद और राज्य विधानसभा चुनावों के लिए अलग-अलग दलों को चुनते हैं, कहलाती है:
(A) विभक्त मतदान
(B) सत्ता विरोधी लहर
(C) सत्ता समर्थक लहर
(D) कूटनीतिक मतदान

179. भारत में 'राष्ट्रीय एकीकरण' की समस्या किसके तुरंत बाद विशेष रूप से तीव्र हो गई थी?
(A) 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन।
(B) 1952 के पहले आम चुनाव।
(C) 1947 में देश का विभाजन।
(D) 1956 में राज्यों का भाषाई पुनर्गठन।

180. निम्नलिखित सूचियों का मिलान करें और सही विकल्प चुनें।
सूची I: (राजनीतिक नेता)
P. जयप्रकाश नारायण
Q. ई.वी. रामास्वामी नायकर
R. बी.आर. अंबेडकर
S. एम.के. गांधी
सूची II: (संबद्ध आंदोलन/विचारधारा)
1. आत्म-सम्मान आंदोलन
2. जाति का विनाश
3. सर्वोदय या संपूर्ण क्रांति
4. ग्राम स्वराज
(A) P-3, Q-1, R-2, S-4
(B) P-1, Q-3, R-4, S-2
(C) P-3, Q-2, R-1, S-4
(D) P-2, Q-4, R-3, S-1

181. 'भारत की आकस्मिकता निधि' का प्रावधान कार्यपालिका को बिना किसी पूर्व अनुमति के अप्रत्याशित व्यय करने की अनुमति देता है:
(A) राष्ट्रपति की स्वीकृति
(B) कैबिनेट की स्वीकृति
(C) संसदीय प्राधिकरण
(D) सर्वोच्च न्यायालय की अनुमति

182. 'सार और तत्व का सिद्धांत' न्यायालयों द्वारा निम्नलिखित निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक विधिक सिद्धांत है:
(A) एक नागरिक के मौलिक अधिकार।
(B) कानून की वास्तविक प्रकृति और चरित्र यह पता लगाने के लिए कि वह किस सूची के अंतर्गत आता है।
(C) संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया।
(D) न्यायिक पुनरावलोकन का आधार।

183. निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है?
(A) अनुच्छेद 352 - राष्ट्रीय आपातकाल
(B) अनुच्छेद 356 - राज्य आपातकाल (राष्ट्रपति शासन)
(C) अनुच्छेद 360 - वित्तीय आपातकाल
(D) अनुच्छेद 368 - युद्ध के कारण आपातकाल

184. अनुच्छेद 21 में "कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया" वाक्यांश की व्याख्या किस प्रसिद्ध मामले में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को शामिल करने के लिए की गई थी?
(A) मेनका गांधी मामला
(B) ए.के. गोपालन मामला
(C) गोलकनाथ मामला
(D) केशवानंद भारती मामला

185. निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन शामिल हैं - अभिकथन (A) और कारण (R)। उचित विकल्प का चयन करके प्रश्न का उत्तर दें।

NODIA

(B) असम
(C) सिक्किम
(D) बिहार

137. चुनावी सुधारों पर किस समिति ने चुनावों के राज्य वित्तपोषण का सुझाव दिया था?
(A) तारकुंडे समिति
(B) दिनेश गोस्वामी समिति
(C) इंद्रजीत गुप्त समिति
(D) वोहरा समिति

138. राष्ट्रीय आंदोलन ने भारतीय संविधान के निर्माण में किस प्रकार योगदान दिया?
(A) लोकतंत्र और समानता जैसे मूल्यों को बढ़ावा देकर जो मार्गदर्शक सिद्धांत बने
(B) पूरे संविधान का एक पूर्ण प्रारूप प्रदान करके
(C) बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं को प्रशिक्षित करके जो बाद में संविधान लिख सकें
(D) संप्रभु संविधान सभा के सदस्यों को सीधे नियुक्त करके

139. निम्नलिखित में से कौन सी रिट किसी निजी व्यक्ति के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है?
(A) परमादेश
(B) उत्प्रेषण
(C) प्रतिषेध
(D) बंदी प्रत्यक्षीकरण

140. संविधान के निम्नलिखित भागों पर विचार करें:
1. संघ और उसका राज्य क्षेत्र
2. मौलिक अधिकार
3. राज्य के नीति निदेशक तत्व
4. नागरिकता

निम्नलिखित में से कौन संविधान में उनके आने का सही क्रम दर्शाता है?
(A) 1, 2, 4, 3
(B) 1, 4, 2, 3
(C) 4, 1, 2, 3
(D) 1, 4, 3, 2

141. भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याकार और संरक्षक कौन है?
(A) संसद
(B) राष्ट्रपति
(C) सर्वोच्च न्यायालय
(D) प्रधानमंत्री

142. किसी राज्य में "मंत्रिपरिषद" सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है?
(A) राज्यपाल
(B) मुख्यमंत्री
(C) विधान परिषद
(D) विधानसभा

143. भारत में मीडिया की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
I. यह लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में कार्य करता है।
II. यह सूचना प्रसारित करने और जनमत को आकार देने का एक प्रमुख माध्यम है।
III. यह सरकारी नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त है।
उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) केवल I
(B) केवल I और II
(C) केवल II और III
(D) I, II और III

144. संसद के विशेष बहुमत और आधे राज्य विधानमंडलों के अनुसमर्थन की आवश्यकता वाली संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस पर लागू होती है?
(A) नए राज्यों का निर्माण।
(B) राष्ट्रपति का चुनाव और उसकी प्रक्रिया
(C) मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रावधान।
(D) संसद में प्रक्रिया के नियम।

145. प्रधानमंत्री के पद के संदर्भ में 'प्राइमस इंटर पेयर्स' सिद्धांत का क्या अर्थ है?
(A) देश का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति।
(B) समानों में प्रथम।
(C) एकमात्र निर्णय लेने वाला।
(D) प्रधान सेनापति।

146. इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ने मुख्य रूप से किस मुद्दे पर विचार किया था?
(A) अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण
(B) अनुच्छेद 356 का संवैधानिक दायरा
(C) प्रेस की स्वतंत्रता
(D) संविधान का मूल ढांचा

147. 1928 में सरदार वल्लभभाई पटेल के नेतृत्व में गुजरात के बारदोली जिले में हुआ किसान आंदोलन किसके विरुद्ध था?
(A) अस्पृश्यता की प्रथा।
(B) नील की जबरन खेती।
(C) भू-राजस्व में वृद्धि।
(D) जमींदारों का मंदिरों में प्रवेश।

148. राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दलों के रूप में मान्यता देने के लिए कौन सा निकाय उत्तरदायी है?
(A) संसद
(B) राष्ट्रपति
(C) सर्वोच्च न्यायालय
(D) भारत का निर्वाचन आयोग

Downloaded from www.pdf.tube

(C) लोकसभा में निर्णायक मत का प्रयोग करना।
(D) अन्य मंत्रियों की नियुक्ति पर राष्ट्रपति को सलाह देना।

124. जनहित याचिका की अवधारणा किस देश में उत्पन्न हुई?
(A) भारत
(B) संयुक्त राज्य अमेरिका
(C) यूनाइटेड किंगडम
(D) ऑस्ट्रेलिया

125. भारतीय संविधान का वैचारिक आधार, जैसा कि प्रस्तावना में परिलक्षित होता है, अपने सभी नागरिकों के लिए क्या सुनिश्चित करना चाहता है?
(A) धन, शक्ति और प्रतिष्ठा
(B) कर्तव्य, अनुशासन और भक्ति
(C) न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व
(D) परंपरा, संस्कृति और विरासत

126. निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें।
कथन I: राज्य के नीति निदेशक तत्व देश के शासन में मौलिक हैं।
कथन II: राज्य के नीति निदेशक तत्व उनके उल्लंघन के लिए न्यायालयों द्वारा सीधे प्रवर्तनीय हैं।
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
(D) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।

127. डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान का 'हृदय और आत्मा' बताया था?
(A) अनुच्छेद 32
(B) अनुच्छेद 14
(C) अनुच्छेद 19
(D) अनुच्छेद 21

128. भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ प्रारंभ की जा सकती है?
(A) केवल लोकसभा में।
(B) केवल राज्यसभा में।
(C) संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में।
(D) संसद के किसी भी सदन में।

129. केंद्र-राज्य संबंधों के संदर्भ में, 'क्षेत्रीय संबंध का सिद्धांत' किस पर लागू होता है?
(A) राज्य का प्रशासनिक क्षेत्राधिकार।
(B) राज्य विधायिका की विधायी क्षमता।
(C) केंद्र से राज्यों को मिलने वाला वित्तीय अनुदान।
(D) राज्यपालों की नियुक्ति।

130. निम्नलिखित में से कौन एक 'संस्थागत' दबाव समूह का उदाहरण है?
(A) नौकरशाही
(B) एक छात्र विरोध समूह
(C) दार्शनिक के नेतृत्व में एक सामाजिक आंदोलन
(D) एक स्वतः स्फूर्त दंगा

131. आदर्श आचार संहिता कब से प्रभावी होती है?
(A) पिछले आम चुनाव की तिथि से।
(B) जिस दिन राष्ट्रपति चुनाव अधिसूचना पर हस्ताक्षर करते हैं।
(C) जैसे ही निर्वाचन आयोग चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करता है।
(D) प्रचार के पहले दिन से।

132. राष्ट्रीय एकीकरण की समस्याओं के संदर्भ में 'जातिवाद' शब्द का अर्थ है:
(A) सामाजिक समूहों का श्रेणीबद्ध क्रम।
(B) सामाजिक न्याय के लिए जातिगत पहचान का दावा।
(C) एक सामाजिक घटना के रूप में जाति का अध्ययन।
(D) अपनी जाति के प्रति अत्यधिक वफादारी जो संघर्ष का कारण बनती है और राष्ट्रीय हित को क्षति पहुँचाती है।

133. निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन शामिल हैं - अभिकथन (A) और कारण (R)। उचित विकल्प का चयन करके प्रश्न का उत्तर दें।
अभिकथन (A): भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है।
कारण (R): भारतीय संविधान देश का सर्वोच्च कानून है, और इसके साथ असंगत किसी भी कानून को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया जा सकता है।
(A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(D) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

134. निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संसदीय प्रणाली की विशेषता नहीं है?
(A) बहुमत दल का शासन
(B) दोहरी सदस्यता
(C) सामूहिक उत्तरदायित्व
(D) शक्तियों का कठोर पृथक्करण

135. 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम पंचायतों में महिलाओं के लिए कम से कम कितनी सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है?
(A) एक-चौथाई
(B) एक-तिहाई
(C) आधा
(D) दो-तिहाई

136. एक पृथक राज्य 'गोरखालैंड' की मांग किस भारतीय राज्य में एक आवर्ती मुद्दा रहा है?
(A) पश्चिम बंगाल

NODIA

लिए, उन्हें संचालित करने वाला निकाय कार्यकारी नियंत्रण से स्वतंत्र होना चाहिए।
(A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(D) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

161. राष्ट्र-निर्माण के लिए चुनौती के रूप में 'क्षेत्रवाद' की समस्या का तात्पर्य है:
(A) देश का राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासनिक विभाजन।
(B) राष्ट्रीय एकता की कीमत पर एक विशिष्ट क्षेत्र के प्रति वफादारी।
(C) क्षेत्रीय भाषाओं और संस्कृतियों का विकास।
(D) पिछड़े क्षेत्रों के लिए अधिक वित्तीय सहायता की मांग।

162. "क्रीमी लेयर" की अवधारणा किससे संबंधित है?
(A) आरक्षण के लाभों से पिछड़े वर्ग के संपन्न सदस्यों का अपवर्जन।
(B) आयकर स्लैब का निर्धारण।
(C) कृषि भूमि का वर्गीकरण।
(D) न्यायिक नियुक्तियों की प्रक्रिया।

163. भारत की संविधान सभा का गठन किसके द्वारा तैयार की गई योजना के तहत किया गया था?
(A) क्रिप्स मिशन
(B) माउंटबेटन योजना
(C) कैबिनेट मिशन योजना
(D) वेवेल योजना

164. निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है?
(A) लिखित संविधान
(B) एकात्मक झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था
(C) स्वतंत्र न्यायपालिका
(D) संसदीय संप्रभुता

165. बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करने की शक्ति किसमें निहित है?
(A) केवल सर्वोच्च न्यायालय में
(B) केवल उच्च न्यायालयों में
(C) सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों दोनों में
(D) जिला न्यायालयों में

166. एक संवैधानिक संशोधन विधेयक, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद, राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, जो:
(A) अपनी सहमति दे सकते हैं या अपनी सहमति रोक सकते हैं।
(B) अपनी सहमति प्रदान करेंगे।
(C) पुनर्विचार के लिए विधेयक वापस कर सकते हैं।
(D) विधेयक को सर्वोच्च न्यायालय भेज सकते हैं।

167. भारत के प्रधानमंत्री को पद की शपथ कौन दिलाता है?
(A) लोकसभा अध्यक्ष
(B) भारत के मुख्य न्यायाधीश
(C) निवर्तमान प्रधानमंत्री
(D) भारत के राष्ट्रपति

168. संघवाद का सिद्धांत किसके बीच संप्रभुता के विभाजन का अर्थ है:
(A) राष्ट्रीय सरकार और क्षेत्रीय सरकारें।
(B) कार्यपालिका और न्यायपालिका।
(C) विधायिका के दो सदन।
(D) राजनीतिक दल और राज्य।

169. न्यायिक सुधारों का मुख्य उद्देश्य क्या है?
(A) न्याय वितरण प्रणाली को अधिक कुशल, सुलभ और कम खर्चीला बनाना।
(B) न्यायाधीशों की संख्या कम करना।
(C) न्याय वितरण प्रणाली को अधिक कुशल, सुलभ और कम खर्चीला बनाना।
(D) देश में न्यायालयों की संख्या कम करना।

170. नीति निर्माण को प्रभावित करने के लिए दबाव समूहों द्वारा उपयोग की जाने वाली सबसे प्रभावी विधि निम्नलिखित में से कौन सी है?
(A) पैरवी
(B) चुनाव लड़ना
(C) राजनीतिक दल बनाना
(D) राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ना

171. सरकार द्वारा अपनी नीतियों और उपलब्धियों के प्रचार-प्रसार के लिए मीडिया का उपयोग किसका उदाहरण है?
(A) मीडिया की प्रहरी भूमिका
(B) मीडिया ट्रायल
(C) पीत पत्रकारिता
(D) जनसंपर्क और आधिकारिक संचार

172. भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
I. यह मतदान के प्रतिरूप और उम्मीदवार के चयन को प्रभावित करती है।
II. इसके कारण जाति-आधारित राजनीतिक दलों का गठन हुआ है।
III. आधुनिकीकरण के साथ इसका प्रभाव पूर्णतः समाप्त हो गया है।
उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) केवल I
(B) केवल I और II
(C) केवल II और III

Click Here to Buy book on Amazon

(C) संसदीय समितियों का कामकाज।
(D) लोक लेखा समिति के सदस्यों का चयन।

99. 'चुनावी व्यवहार' का अध्ययन किस पर केंद्रित है?
(A) चुनाव को नियंत्रित करने वाला विधिक ढांचा।
(B) चुनाव कराने के लिए प्रशासनिक तंत्र।
(C) मतदाताओं की पसंद के पीछे के प्रतिरूप और प्रेरणाएं।
(D) चुनाव कानूनों का ऐतिहासिक विकास।

100. राष्ट्र-निर्माण की समस्या के रूप में सांप्रदायिकता का तात्पर्य है:
(A) राष्ट्र के बजाय अपने क्षेत्र के प्रति वफादारी।
(B) लोगों का स्वशासी समूहों में संगठन।
(C) विकास के लिए विभिन्न समुदायों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा।
(D) राष्ट्रीय हितों के बजाय अपने धार्मिक समुदाय के प्रति निष्ठा।

101. 'उद्देश्य प्रस्ताव', जिसने संविधान के दर्शन की रूपरेखा तैयार की थी, संविधान सभा में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था?
(A) डॉ. बी.आर. अंबेडकर
(B) डॉ. राजेंद्र प्रसाद
(C) जवाहरलाल नेहरू
(D) सरदार पटेल

102. भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता कठोरता और लचीलेपन के बीच संतुलन प्रदान करती है?
(A) न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान।
(B) संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया।
(C) राज्य की अर्ध-संघीय प्रकृति।
(D) संसदीय सरकार की प्रणाली।

103. 'अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण' एक मौलिक अधिकार है जिसकी गारंटी किसके अंतर्गत दी गई है:
(A) अनुच्छेद 19
(B) अनुच्छेद 21
(C) अनुच्छेद 22
(D) अनुच्छेद 20

104. किसी विधेयक को 'धन विधेयक' माना जाता है यदि इसमें निम्नलिखित से संबंधित प्रावधान हों:
(A) किसी कर का अधिरोपण, उत्सादन या विनियमन
(B) नए क्षेत्रीय राज्यों का विधिक गठन
(C) संविधान का सामान्य संशोधन
(D) राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष चुनाव

105. निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें।
कथन I: प्रधानमंत्री भारत में सरकार के प्रमुख होते हैं।
कथन II: राष्ट्रपति भारत में राष्ट्र के प्रमुख होते हैं।
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
(D) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।

106. केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय को बढ़ावा देने के लिए संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अंतर-राज्य परिषद की स्थापना की गई थी?
(A) अनुच्छेद 263
(B) अनुच्छेद 262
(C) अनुच्छेद 280
(D) अनुच्छेद 356

107. निम्नलिखित में से कौन सा मामला भारत में जनहित याचिका के विकास से प्रसिद्ध रूप से जुड़ा हुआ है?
(A) केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य
(B) एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ
(C) इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ
(D) हुसनआरा खातून बनाम गृह सचिव, बिहार

108. एक 'एनोमिक' दबाव समूह की विशेषता क्या है?
(A) सुसंगठित और पेशेवर होना।
(B) विरोध प्रदर्शनों का अचानक और असंगठित रूप से फूटना।
(C) जाति या धर्म के आधार पर गठित होना।
(D) स्थायी कार्यालय और कर्मचारी होना।

109. मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा की गई थी?
(A) 42वां संशोधन अधिनियम
(B) 44वां संशोधन अधिनियम
(C) 61वां संशोधन अधिनियम
(D) 52वां संशोधन अधिनियम

110. निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन शामिल हैं - अभिकथन (A) और कारण (R)। उचित विकल्प का चयन करके प्रश्न का उत्तर दें।
अभिकथन (A): क्षेत्रवाद राष्ट्रीय एकीकरण के लिए चुनौती उत्पन्न कर सकता है।
कारण (R): अपने क्षेत्र के प्रति अत्यधिक लगाव अलगाव की मांगों को जन्म दे सकता है और एक साझा राष्ट्रीय पहचान की भावना को कमजोर कर सकता है।
(A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(D) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

111. 'संवैधानिक समीक्षा' की अवधारणा में मुख्य रूप से शामिल है:
(A) विशेष रूप से गठित आयोग द्वारा संविधान के कामकाज की समय-समय पर समीक्षा करने की प्रक्रिया।
(B) अपनी इच्छानुसार संविधान की समीक्षा करने और उसे बदलने की संसद की शक्ति।

NODIA

अभिकथन (A): भारतीय संविधान संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय है।
कारण (R): जहाँ संसद संविधान के बड़े हिस्से में संशोधन कर सकती है, वहीं सर्वोच्च न्यायालय संसदीय कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है यदि वे मूल संरचना का उल्लंघन करते हैं।
(A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(D) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

186. 'जनहित याचिका' की अवधारणा निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा देने में सहायक रही है:
(A) निर्धनों और वंचितों के अधिकार।
(B) निगमों के हित।
(C) कार्यपालिका की सर्वोच्चता।
(D) पुलिस की शक्तियां।

187. अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस मुख्य रुप से किस राज्य में स्थित एक क्षेत्रीय दल है?
(A) ओडिशा
(B) असम
(C) त्रिपुरा
(D) पश्चिम बंगाल

188. निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है?
(A) निर्वाचन आयोग
(B) संघ लोक सेवा आयोग
(C) नीति आयोग
(D) वित्त आयोग

189. चुनावी व्यवहार के अध्ययन में 'राजनीतिक संस्कृति' शब्द का तात्पर्य है:
(A) राजनीतिक दलों द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम।
(B) राजनीतिक नेताओं की शैक्षणिक योग्यता।
(C) उन दृष्टिकोणों, विश्वासों और भावनाओं का समूह जो राजनीतिक प्रक्रिया को व्यवस्था और अर्थ प्रदान करते हैं।
(D) सरकारी भवनों की स्थापत्य शैली।

190. भारत में लिंग आधारित राजनीतिक मुद्दों में निम्नलिखित को छोड़कर सभी शामिल हैं:
(A) विधायी निकायों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की मांग।
(B) समान नागरिक संहिता पर बहस।
(C) कन्या भ्रूण हत्या की समस्या।
(D) भाषाई आधार पर नए राज्यों का निर्माण।

191. संविधान निर्माताओं के लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत किसका आदर्श थी:
(A) धर्मतंत्रात्मक राज्य
(B) राजतंत्र
(C) सैन्य तानाशाही
(D) संप्रभु, लोकतांत्रिक, गणराज्य

192. निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता है?
(A) यह विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है।
(B) यह सरकार के राष्ट्रपति स्वरूप का प्रावधान करता है।
(C) यह अत्यंत कठोर है और इसमें संशोधन करना अत्यंत कठिन है।
(D) यह विभिन्न स्रोतों से अपनाई गई विशेषताओं का मिश्रण है।

193. सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन का एक उपाय, अस्पृश्यता का अंत, किस मौलिक अधिकार में निहित है?
(A) स्वतंत्रता का अधिकार
(B) समानता का अधिकार
(C) शोषण के विरुद्ध अधिकार
(D) धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार

194. निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें।
कथन I: अनुच्छेद 368 के तहत संवैधानिक संशोधन केवल राष्ट्रपति द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है।
कथन II: एक संवैधानिक संशोधन विधेयक को संसद में पारित होने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है।
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।
(D) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।

195. प्रधानमंत्री के त्यागपत्र से स्वतः क्या परिणाम होता है?
(A) लोकसभा का विघटन।
(B) अध्यक्ष द्वारा नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति।
(C) संपूर्ण मंत्रिपरिषद का विघटन।
(D) एक महीने के भीतर नए चुनाव।

196. वह विधायी सूची जिसमें संघ और राज्यों दोनों के साझा हित के विषय शामिल हैं, वह है:
(A) संघ सूची
(B) राज्य सूची
(C) अवशिष्ट सूची
(D) समवर्ती सूची

197. 'वाद का अधिकार' शब्द को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसके संदर्भ में उदार बनाया गया था?
(A) सामान्य दीवानी मुकदमे
(B) चुनाव याचिकाएं
(C) जनहित याचिका
(D) आपराधिक अपीलें

NODIA

224. संवैधानिक समीक्षा की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
I. यह संविधान के कामकाज का मूल्यांकन करने का एक अभ्यास है।
II. संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन वर्ष 2000 में किया गया था।
III. इस तरह की समीक्षा केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रारंभ की जा सकती है।
उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) केवल I और II
(B) केवल II और III
(C) केवल I और III
(D) I, II और III

225. 'प्रश्न काल' का संसदीय उपकरण किस उद्देश्य की पूर्ति करता है?
(A) नए विधेयक पेश करना।
(B) कार्यपालिका की गतिविधियों पर जानकारी मांगकर उसे उत्तरदायी ठहराना।
(C) राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बहस करना।
(D) वार्षिक बजट पारित करना।

226. संघवाद के सिद्धांत के लिए एक लिखित और कठोर संविधान की आवश्यकता मुख्य रूप से किसके लिए होती है:
(A) बार-बार होने वाले एकतरफा संशोधनों को रोकने और शक्तियों के विभाजन की रक्षा करने के लिए
(B) केंद्रीय सरकार की पूर्ण सर्वोच्चता सुनिश्चित करने के लिए
(C) सामान्य शासन प्रक्रिया को जानबूझकर कठिन बनाने के लिए
(D) न्यायपालिका को सभी प्राथमिक विधायी कार्यों को सौंपने के लिए

227. पंजाब और तमिलनाडु जैसे राज्यों में स्वायत्तता की मांग ऐतिहासिक रूप से किस पर केंद्रित रही है?
(A) एक पृथक मुद्रा का निर्माण।
(B) भारतीय संघ से पृथक होना।
(C) राज्यों को अधिक शक्तियां देने के लिए केंद्र-राज्य संबंधों का पुनर्गठन करना।
(D) राज्य में राजतंत्र स्थापित करना।

228. 'न्यायिक सुधार' की अवधारणा का उद्देश्य किस समस्या से निपटना है?
(A) न्यायिक अतिरेक।
(B) न्यायाधीशों के लिए कम वेतन।
(C) मामलों का भारी लंबित होना और न्याय में विलंब।
(D) न्यायिक नियुक्तियों में राजनीतिक हस्तक्षेप।

229. निम्नलिखित में से कौन सी विधि सामान्यतः दबाव समूहों द्वारा उपयोग नहीं की जाती है?
(A) विधायकों और मंत्रियों के साथ पैरवी करना।
(B) विरोध प्रदर्शन आयोजित करना।
(C) जनमत को आकार देने के लिए मीडिया का उपयोग करना।
(D) सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति करना।

230. सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, जो भारतीय चुनावों की एक प्रमुख विशेषता है, का अर्थ है:
(A) केवल संपत्ति के स्वामी ही मतदान कर सकते हैं।
(B) सभी वयस्कों को बिना किसी भेदभाव के मतदान करने का अधिकार है।
(C) केवल शिक्षित व्यक्ति ही मतदान कर सकते हैं।
(D) सभी के लिए मतदान अनिवार्य है।

231. भारतीय संदर्भ में 'पहचान की राजनीति' अक्सर किस पर आधारित राजनीतिक लामबंदी को संदर्भित करती है:
(A) आर्थिक नीतियां और विकास मॉडल।
(B) विदेश नीति के रुझान।
(C) किसी एक राष्ट्रीय नेता के प्रति निष्ठा।
(D) जाति, धर्म, भाषा या क्षेत्र सहित साझा पहचान।

232. 1956 में राज्यों का भाषाई पुनर्गठन राष्ट्र-निर्माण की किस समस्या के समाधान में एक बड़ा कदम था?
(A) भाषा पर आधारित क्षेत्रवाद
(B) सांप्रदायिकता
(C) जातिवाद
(D) आर्थिक असमानता

233. भारत सरकार अधिनियम, 1919 को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है:
(A) मार्ले-मिंटो सुधार
(B) साइमन कमीशन रिपोर्ट
(C) मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार
(D) सांप्रदायिक पंचाट

234. भारतीय संविधान को 'अर्ध-संघीय' कहा जाता है क्योंकि:
(A) यह एक सुदृढ़ एकात्मक झुकाव के साथ संघीय विशेषताओं को जोड़ता है।
(B) इसमें बहुत सुदृढ़ न्यायपालिका है।
(C) इसमें सरलता से संशोधन किया जा सकता है।
(D) इसका कोई लिखित रूप नहीं है।

235. मौलिक कर्तव्यों के प्रवर्तन को किसके माध्यम से प्रोत्साहित किया जा सकता है:
(A) केवल संवैधानिक संशोधनों द्वारा।
(B) केवल सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों द्वारा।
(C) केवल राष्ट्रपति के अध्यादेशों द्वारा।
(D) विधायी अधिनियमों और सामाजिक एवं शैक्षिक वातावरण द्वारा।

236. निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन शामिल हैं - अभिकथन (A) और कारण (R)। उचित विकल्प का चयन करके प्रश्न का उत्तर दें।

Downloaded from www.pdf.tube

है
(D) धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार - दूसरों को धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार शामिल है

212. निम्नलिखित में से किस मामले में संसद के साधारण बहुमत द्वारा संविधान में संशोधन किया जा सकता है?
(A) राष्ट्रपति का निर्वाचन।
(B) सातवीं अनुसूची में परिवर्तन।
(C) मौलिक अधिकारों का संशोधन।
(D) नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना।

213. निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें।
कथन I: भारत के राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं।
कथन II: राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग हैं।
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
(D) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।

214. संघ और राज्यों के बीच वित्तीय संबंध संविधान के किस भाग में वर्णित हैं?
(A) भाग X
(B) भाग XII
(C) भाग XI
(D) भाग XIII

215. 'उत्प्रेषण' की रिट किसके विरुद्ध जारी की जा सकती है:
(A) केवल विधायी निकाय
(B) निजी व्यक्ति और कंपनियां
(C) न्यायिक और अर्ध-न्यायिक प्राधिकारी
(D) केवल प्रशासनिक निकाय

216. निम्नलिखित सूचियों का मिलान करें और सही विकल्प चुनें।
सूची I: (दलीय प्रणाली का प्रकार)
P. एक-दलीय प्रणाली
Q. द्वि-दलीय प्रणाली
R. बहु-दलीय प्रणाली
S. प्रभावी दलीय प्रणाली
सूची II: (उदाहरण देश)
1. संयुक्त राज्य अमेरिका
2. भारत (1989 के बाद)
3. चीन
4. भारत (1952-1967)
(A) P-3, Q-1, R-2, S-4
(B) P-1, Q-3, R-4, S-2
(C) P-3, Q-2, R-1, S-4
(D) P-2, Q-4, R-3, S-1

217. भारत में मीडिया के विरुद्ध एक प्रमुख आलोचना निम्नलिखित में से कौन सी है?
(A) यह ग्रामीण मुद्दों को अत्यधिक स्थान देता है।
(B) यह पूर्णतः सरकार द्वारा नियंत्रित है।
(C) स्वामित्व का संकेंद्रण और पेड न्यूज के मुद्दे।
(D) यह मनोरंजन और खेल को कवर नहीं करता है।

218. 'चुनावी व्यवहार' शब्द सबसे अधिक किस शैक्षणिक विषय से जुड़ा है?
(A) राजनीतिक समाजशास्त्र
(B) लोक प्रशासन
(C) अंतरराष्ट्रीय संबंध
(D) संवैधानिक कानून

219. भारत में 'जेंडर बजटिंग' का मुद्दा किसका एक प्रयास है:
(A) महिलाओं के लिए एक पृथक बजट बनाना।
(B) बजट का एक निश्चित प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षित करना।
(C) केवल महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों के लिए धन प्रदान करना।
(D) बजट के लिंग-विभेदित प्रभाव का आकलन करना।

220. रियासतों का भारतीय संघ में एकीकरण राष्ट्र-निर्माण की एक बड़ी समस्या थी, जिसे मुख्य रूप से किसके द्वारा सुलझाया गया था:
(A) जवाहरलाल नेहरू
(B) सरदार वल्लभभाई पटेल
(C) डॉ. बी.आर. अंबेडकर
(D) सी. राजगोपालाचारी

NODIA

221. भारत की संप्रभुता का स्रोत, जैसा कि प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है, किसमें निहित है:
(A) संविधान
(B) राष्ट्रपति
(C) भारत के लोग
(D) संसद

222. संविधान का कौन सा भाग 'संविधान की अंतरात्मा' को दर्शाता है?
(A) प्रस्तावना और मौलिक कर्तव्य
(B) संघ कार्यपालिका से संबंधित प्रावधान
(C) आपातकालीन प्रावधान
(D) मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निदेशक तत्व

223. मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्व के बीच प्राथमिक अंतर क्या है?
(A) मौलिक अधिकार न्यायोचित हैं जबकि नीति निदेशक तत्व गैर-न्यायोचित हैं।
(B) मौलिक अधिकार नागरिकों के लिए हैं जबकि नीति निदेशक तत्व विदेशियों के लिए हैं।
(C) मौलिक अधिकार नकारात्मक दायित्व हैं जबकि नीति निदेशक तत्व सकारात्मक हैं।
(D) इनमें कोई अंतर नहीं है; ये विनिमेय हैं।

275. प्रधानमंत्री की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
I. वह राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संचार का मुख्य माध्यम है।
II. वह संसद के सत्रों को बुलाने और सत्रावसान करने के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देता है।
III. सभी न्यायिक नियुक्तियों में उसकी अंतिम भूमिका होती है।
उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) केवल I और II
(B) केवल II और III
(C) केवल I
(D) I, II और III

276. भारत में 'असममित संघवाद' की अवधारणा किसमें परिलक्षित होती है:
(A) राज्यसभा में सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व।
(B) सभी राज्यों पर सभी कानूनों का समान रूप से लागू होना।
(C) एकल और एकीकृत न्यायिक प्रणाली।
(D) उत्तर-पूर्व के राज्यों जैसे कुछ राज्यों के लिए विशिष्ट संवैधानिक प्रावधान।

277. 'सुधारात्मक याचिका' भारत में एक न्यायिक नवाचार है जिसे दायर किया जा सकता है:
(A) विचारण प्रारंभ होने से पहले।
(B) सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में।
(C) सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन याचिका खारिज किए जाने के बाद।
(D) किसी भी नागरिक द्वारा सरकारी नीति के विरुद्ध।

278. चिपको आंदोलन किसका एक प्रसिद्ध उदाहरण है:
(A) भूमि अधिकारों के लिए किसान आंदोलन।
(B) पर्यावरण आंदोलन।
(C) सामाजिक न्याय के लिए दलित आंदोलन।
(D) राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए महिला आंदोलन।

279. वीवीपीएटी की शुरुआत एक चुनावी सुधार है जिसका उद्देश्य है:
(A) मतों की गणना की गति बढ़ाना।
(B) मतदाताओं को घर से मतदान करने की अनुमति देना।
(C) निर्वाचन आयोग को प्रतिस्थापित करना।
(D) मतदान प्रक्रिया की पारदर्शिता और सत्यापन योग्यता को बढ़ाना।

280. राज्यों के भाषाई पुनर्गठन ने राष्ट्र-निर्माण की किस अन्य चुनौती को तीव्र कर दिया?
(A) क्षेत्रवाद और अंतर-राज्य विवाद
(B) सांप्रदायिकता
(C) जातिवाद
(D) आर्थिक मंदी

281. भारतीय संविधान कब लागू हुआ?
(A) 26 जनवरी 1949
(B) 26 नवंबर 1949
(C) 15 अगस्त 1947
(D) 26 जनवरी 1950

282. 'पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन' का प्रावधान किसमें सम्मिलित है:
(A) राज्य के नीति निदेशक तत्व
(B) प्रस्तावना
(C) मौलिक अधिकार
(D) मौलिक कर्तव्य

283. निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें।
कथन I: भारत की संसद एक द्विसदनीय विधायिका है।
कथन II: राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाता है।
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
(D) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।

284. निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का आधार नहीं है?
(A) युद्ध
(B) आंतरिक अशांति
(C) बाहरी आक्रमण
(D) सशस्त्र विद्रोह

285. सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन से विवाद आते हैं:
(A) भारत के दो नागरिकों के बीच।
(B) मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित।
(C) भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच।
(D) किसी संधि या समझौते से उत्पन्न होने वाले।

286. निम्नलिखित सूचियों का मिलान करें और सही विकल्प चुनें।
सूची I: (ऐतिहासिक मामला)
P. एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ
Q. विशाखा बनाम राजस्थान राज्य
R. मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ
S. डी.सी. वाधवा बनाम बिहार राज्य
सूची II: (मुख्य विषय)
1. मौलिक अधिकारों और नीति निदेशक तत्वों के बीच सद्भाव
2. अध्यादेश बनाने की शक्ति का दुरुपयोग
3. अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग
4. कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न
(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-3, Q-4, R-1, S-2
(C) P-3, Q-1, R-4, S-2
(D) P-4, Q-3, R-2, S-1

Click Here to Buy book on Amazon

अभिकथन (A): न्यायिक पुनरावलोकन भारतीय संविधान की एक मूल विशेषता है।
कारण (R): न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को संवैधानिक संशोधन द्वारा भी समाप्त नहीं किया जा सकता है।
(A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(D) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

237. संसदीय प्रणाली के कामकाज में, 'छाया मंत्रिमंडल' किस देश की राजनीतिक प्रणाली से जुड़ी एक विशेषता है?
(A) भारत
(B) संयुक्त राज्य अमेरिका
(C) ब्रिटेन
(D) फ्रांस

238. निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय है जो संघ और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण पर राष्ट्रपति को सिफारिशें करता है?
(A) नीति आयोग
(B) अंतर-राज्य परिषद
(C) राष्ट्रीय विकास परिषद
(D) वित्त आयोग

239. 'न्यायिक अतिरेक' एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग न्यायपालिका की आलोचना करने के लिए किया जाता है जब वह:
(A) विधायिका या कार्यपालिका की शक्तियों का अतिक्रमण करती हुई प्रतीत होती है।
(B) जनहित याचिका सुनने से मना करती है।
(C) सरकार के विरुद्ध निर्णय देती है।
(D) किसी मामले का निर्णय करने में लंबा समय लेती है।

240. भारत में 'एक-दलीय प्रभावी प्रणाली' से 'बहु-दलीय गठबंधन प्रणाली' में संक्रमण मुख्य रूप से किस आम चुनाव के बाद हुआ:
(A) 1967
(B) 1989
(C) 1977
(D) 2004

241. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर 'नोटा' विकल्प चुनावी सुधारों का एक हिस्सा है जिसका उद्देश्य है:
(A) मतदाताओं को सभी उम्मीदवारों को अस्वीकार करने की अनुमति देना।
(B) मतदान अनिवार्य बनाना।
(C) ऑनलाइन मतदान सक्षम करना।
(D) आनुपातिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत करना।

242. महिला आरक्षण विधेयक में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव है:
(A) लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में।
(B) न्यायपालिका और नौकरशाही में।
(C) सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में।
(D) केवल राज्यसभा और विधान परिषदों में।

243. "उद्देश्य प्रस्ताव" ने बाद में संविधान के किस भाग का रूप लिया?
(A) मौलिक अधिकार
(B) राज्य के नीति निदेशक तत्व
(C) प्रस्तावना
(D) आपातकालीन प्रावधान

244. 'मानव तस्करी और बलात् श्रम का प्रतिषेध' का प्रावधान किसके तहत एक मौलिक अधिकार है:
(A) समानता का अधिकार
(B) स्वतंत्रता का अधिकार
(C) संवैधानिक उपचारों का अधिकार
(D) शोषण के विरुद्ध अधिकार

245. निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें।
कथन I: 42वां संशोधन अधिनियम भारतीय संविधान का सबसे व्यापक संशोधन है।
कथन II: 44वें संशोधन अधिनियम ने 42वें संशोधन द्वारा लाए गए कई परिवर्तनों को सुधारने का प्रयास किया।
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
(D) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।

246. भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं?
(A) 2
(B) 12
(C) 10
(D) 14

247. आनंदपुर साहिब प्रस्ताव किसकी मांग से जुड़ा है:
(A) तेलंगाना का निर्माण।
(B) बिहार में जमींदारी का उन्मूलन।
(C) विदर्भ का एक पृथक राज्य।
(D) पंजाब के लिए अधिक राज्य स्वायत्तता।

248. लोकतंत्र में मीडिया की प्राथमिक भूमिका को अक्सर किस रूप में वर्णित किया जाता है:
(A) चतुर्थ स्तंभ
(B) प्रथम स्तंभ
(C) द्वितीय स्तंभ
(D) तृतीय स्तंभ

NODIA

198. एक गैर-साहचर्य दबाव समूह का उदाहरण क्या होगा:
(A) अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस जैसा श्रमिक संघ।
(B) छात्रों के एक समूह द्वारा स्वतः स्फूर्त विरोध।
(C) फिक्की जैसा व्यापार संघ।
(D) इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जैसा पेशेवर निकाय।

199. 'मतदाता सूची' शब्द का क्या अर्थ है?
(A) चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची।
(B) मतदान केंद्रों की सूची।
(C) चुनाव के लिए आचार संहिता।
(D) एक निर्वाचन क्षेत्र में पात्र मतदाताओं की सूची।

200. राजनीतिक पहचान के रूप में 'दलित' की अवधारणा किससे बदलाव का संकेत देती है?
(A) निम्न स्थिति की निष्क्रिय स्वीकृति से एक मुखर राजनीतिक चेतना की ओर
(B) आर्थिक वर्ग से धार्मिक पहचान पर ध्यान केंद्रित करने की ओर
(C) क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांग से राष्ट्रीय सत्ता की मांग की ओर
(D) ग्रामीण आधारित आंदोलन से शहरी आंदोलन की ओर

201. संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नीति निदेशक तत्व जोड़ा गया था?
(A) ग्राम पंचायतों का संगठन
(B) समान नागरिक संहिता
(C) समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता
(D) अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना

202. लोकसभा की बैठक गठित करने के लिए गणपूर्ति क्या है:
(A) कुल सदस्य संख्या का दसवां भाग।
(B) कुल सदस्य संख्या का आधा भाग।
(C) कुल सदस्य संख्या का एक-तिहाई भाग।
(D) कुल सदस्य संख्या का एक-चौथाई भाग।

203. भारत में क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना किसके द्वारा की गई थी?
(A) भारत के संविधान द्वारा
(B) केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा
(C) एक राष्ट्रपति के आदेश द्वारा
(D) राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 द्वारा

204. निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पर है?
(A) दिल्ली उच्च न्यायालय
(B) गुवाहाटी उच्च न्यायालय
(C) इलाहाबाद उच्च न्यायालय
(D) मद्रास उच्च न्यायालय

205. बंगाल में 'तेभागा आंदोलन' एक महत्वपूर्ण किसान विद्रोह था जिसकी मांग थी:
(A) जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन।
(B) वन भूमि पर कृषि करने का अधिकार।
(C) जमींदारों को दिए जाने वाले फसल के हिस्से को आधे से घटाकर एक-तिहाई करना।
(D) सभी किसान ऋणों की माफी।

206. निर्वाचन आयोग द्वारा किसी दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त नहीं है?
(A) यह एक आम चुनाव में किन्हीं चार या अधिक राज्यों में पड़े वैध मतों का कम से कम छह प्रतिशत प्राप्त करता है।
(B) यह कम से कम तीन अलग-अलग राज्यों से लोकसभा में कम से कम दो प्रतिशत सीटें जीतता है।
(C) इसे कम से कम चार राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त है।
(D) यह कम से कम दस वर्षों से अस्तित्व में है।

207. स्वतंत्रता के बाद के भारत में क्षेत्रवाद के उदय का एक प्राथमिक कारण क्या था?
(A) क्षेत्रीय आर्थिक असंतुलन के साथ भाषाई और सांस्कृतिक विविधता
(B) एक कठोर एकात्मक राष्ट्रीय संविधान को अपनाना
(C) एक एकल राष्ट्रीय भाषा को जबरन थोपना
(D) विदेशी शक्तियों का ऐतिहासिक और राजनीतिक प्रभाव

208. संसदीय प्रणाली में विधायिका कार्यपालिका की उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए जिस मुख्य साधन का उपयोग करती है, वह है:
(A) मंत्रियों की नियुक्ति करने की शक्ति।
(B) न्यायपालिका पर नियंत्रण।
(C) सरकारी विभागों का प्रत्यक्ष प्रशासन।
(D) विभिन्न संसदीय प्रक्रियाएं जैसे प्रश्न, प्रस्ताव और वित्तीय नियंत्रण।

209. 'संथानम समिति' की नियुक्ति किस पर प्रतिवेदन देने के लिए की गई थी?
(A) केंद्र-राज्य संबंध
(B) भ्रष्टाचार की रोकथाम
(C) चुनावी सुधार
(D) पंचायती राज संस्थाएं

210. 'लिखित संविधान' की अवधारणा सबसे पहले किस देश ने अपनाई थी?
(A) संयुक्त राज्य अमेरिका
(B) यूनाइटेड किंगडम
(C) फ्रांस
(D) भारत

211. निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म है?
(A) स्वतंत्रता का अधिकार - राजनीतिक दल बनाने का अधिकार शामिल है
(B) समानता का अधिकार - उपाधियों का अंत शामिल है
(C) शोषण के विरुद्ध अधिकार - काम का अधिकार शामिल

Downloaded from www.pdf.tube

है।
(C) उनके कार्यान्वयन के लिए विधान की आवश्यकता होती है।
(D) वे संविधान के प्रारंभ होने पर स्वतः ही लागू हो जाते हैं।

263. भारत में नया राज्य बनाने के उद्देश्य से एक विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जाना चाहिए:
(A) केवल राज्यसभा में।
(B) केवल लोकसभा में।
(C) राष्ट्रपति की सिफारिश पर संसद के किसी भी सदन में।
(D) संबंधित राज्य के विधानमंडल में।

264. भारत में संसदीय प्रणाली के कामकाज की मुख्य विशेषता क्या है?
(A) विधायिका और कार्यपालिका के बीच सद्भाव और सहयोग।
(B) राष्ट्रपति का प्रभुत्व।
(C) विधायिका और कार्यपालिका के बीच कठोर पृथक्करण।
(D) कार्यपालिका पर न्यायिक नियंत्रण।

265. किसी राज्य का राज्यपाल किस रुप में कार्य करता है:
(A) राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में।
(B) एक स्वतंत्र प्राधिकारी के रुप में।
(C) राष्ट्रपति और केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में।
(D) राज्य न्यायपालिका के प्रमुख के रूप में।

266. निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन शामिल हैं - अभिकथन (A) और कारण (R)। उचित विकल्प का चयन करके प्रश्न का उत्तर दें।
अभिकथन (A): न्यायिक सक्रियता ने समय-समय पर सरकार के अंगों के बीच शक्तियों के पृथक्करण की रेखा को अस्पष्ट कर दिया है।
कारण (R): अधिकारों को लागू करने के क्रम में, न्यायपालिका ने कभी-कभी उन मामलों पर निर्देश जारी किए हैं जो नीति निर्माण जैसे कार्यकारी और विधायी क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं।
(A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(D) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

267. निम्नलिखित में से कौन सा दबाव समूह का मान्यता प्राप्त प्रकार नहीं है?
(A) संस्थागत समूह
(B) साहचर्य समूह
(C) गैर-साहचर्य समूह
(D) चुनावी समूह

268. चुनाव के संदर्भ में 'एग्जिट पोल' किसके द्वारा किया गया सर्वेक्षण है:
(A) परिणाम की भविष्यवाणी करने के लिए मतदान के दिन से पहले।
(B) मतदाताओं के मतदान करने के तुरंत बाद उनके बीच।
(C) परिणाम घोषित होने के बाद विजयी उम्मीदवारों के बीच।
(D) अनियमितताओं की जांच के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा।

269. 'शाह बानो मामला' भारतीय राजनीति में निम्नलिखित में से किससे संबंधित एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया था?
(A) केंद्र-राज्य संबंध
(B) जाति-आधारित आरक्षण
(C) लिंग न्याय और समान नागरिक संहिता
(D) चुनावी सुधार

270. भारत में राष्ट्रीय एकीकरण की मुख्य समस्याओं में से एक 'सांप्रदायिकता' है, जिसे किसके द्वारा बढ़ावा दिया जाता है:
(A) विभिन्न समुदायों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा।
(B) धर्मनिरपेक्ष उद्देश्यों के लिए धार्मिक पहचान के आधार पर राजनीतिक लामबंदी।
(C) धार्मिक स्वतंत्रता की संवैधानिक मान्यता।
(D) यह विश्वास कि एक धार्मिक समूह के हित अन्य समूहों के विरोधी हैं।

271. संविधान सभा एक 'संप्रभु' निकाय थी, जिसका अर्थ था कि:
(A) वह अपनी इच्छानुसार कोई भी संविधान बना सकती थी, जो बाहरी नियंत्रण से मुक्त हो।
(B) इसे ब्रिटिश संसद द्वारा निर्मित किया गया था।
(C) इसके निर्णय वायसराय के अनुमोदन के अधीन थे।
(D) इसमें सभी देशों के सदस्य थे।

272. भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता किसका समन्वय है:
(A) अमेरिकी राष्ट्रपति शासन और ब्रिटिश राजतंत्र।
(B) पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और कम्युनिस्ट राजनीति।
(C) एक कठोर और एक लचीली संशोधन प्रक्रिया।
(D) संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता।

273. संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किसके द्वारा हटा दिया गया था:
(A) 42वां संशोधन अधिनियम
(B) 44वां संशोधन अधिनियम
(C) 52वां संशोधन अधिनियम
(D) 25वां संशोधन अधिनियम

274. एक संवैधानिक संशोधन जो संविधान के संघीय स्वरूप को प्रभावित करता है, उसे किसके विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थित किया जाना चाहिए:
(A) कम से कम आधे राज्यों के।
(B) सभी राज्यों के।
(C) कम से कम दो-तिहाई राज्यों के।
(D) किन्हीं दस राज्यों के।

NODIA

(D) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

299. चुनावी व्यवहार के संदर्भ में, 'सत्ता विरोधी लहर' उस भावना को संदर्भित करती है जो:
(A) सत्तारूढ़ दल या उम्मीदवार के पक्ष में हो।
(B) चुनाव के प्रति उदासीनता वाली हो।
(C) तीसरे मोर्चे के पक्ष में हो।
(D) सत्तारूढ़ दल या उम्मीदवार के विरुद्ध हो।

300. सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन के साधन के रूप में संविधान का अंतिम लक्ष्य एक 'समतावादी समाज' स्थापित करना है, जिसका अर्थ है:
(A) आय और धन की पूर्ण समानता वाला समाज।
(B) एक ऐसा समाज जहाँ सभी के साथ समान व्यवहार किया जाता है और सभी को समान अवसर प्राप्त होते हैं।
(C) कुछ चुनिंदा बुद्धिजीवियों द्वारा शासित समाज।
(D) एक ऐसा समाज जिसने आधुनिक तकनीक को अस्वीकार कर दिया है।

www.nodia.in

Click Here to Buy book on Amazon

287. निम्नलिखित में से कौन सा दबाव समूह का मुख्य कार्य है?
(A) हितों की अभिव्यक्ति और उनका समुच्चयन।
(B) सरकार बनाना।
(C) राजनीतिक नेताओं की भर्ती करना।
(D) चुनाव लड़ना।

288. भारत में चुनावों के लिए निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किसके द्वारा किया जाता है:
(A) निर्वाचन आयोग।
(B) संसद।
(C) राष्ट्रपति।
(D) एक स्वतंत्र परिसीमन आयोग।

289. राष्ट्र-निर्माण के एक घटक के रूप में 'राजनीतिक एकीकरण' का तात्पर्य है:
(A) सभी क्षेत्रों का आर्थिक विकास।
(B) एक एकल केंद्रीय प्राधिकरण के तहत क्षेत्र को समेकित करना।
(C) सभी समूहों का सांस्कृतिक आत्मसात।
(D) नियमित चुनाव कराना।

290. निम्नलिखित में से किसने राज्य के नीति निदेशक तत्वों को 'बैंक पर एक चेक, जिसका भुगतान बैंक के संसाधनों की अनुमति पर निर्भर है' के रूप में वर्णित किया था?
(A) के.टी. शाह
(B) डॉ. बी.आर. अंबेडकर
(C) जवाहरलाल नेहरू
(D) डॉ. राजेंद्र प्रसाद

291. भारतीय संसदीय प्रणाली 'शक्तियों के संलयन' के सिद्धांत पर कार्य करती है जिसका अर्थ है:
(A) न्यायपालिका विधायिका का एक भाग है।
(B) केंद्र और राज्यों की शक्तियां आपस में मिली हुई हैं।
(C) कार्यपालिका विधायिका से ली जाती है और उसके प्रति उत्तरदायी होती है।
(D) राष्ट्रपति के पास कार्यकारी और विधायी दोनों शक्तियां होती हैं।

292. निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों और केंद्र के बीच सहयोग सुनिश्चित करने के लिए एक संविधानोतर उपकरण है?
(A) वित्त आयोग
(B) अंतर-राज्य परिषद
(C) क्षेत्रीय परिषद
(D) राष्ट्रीय विकास परिषद

293. 'अधिकार-पृच्छा' की रिट जारी करने का उद्देश्य है:
(A) किसी अधिकारी को अपना कर्तव्य निभाने के लिए बाध्य करना।
(B) किसी ऐसे व्यक्ति को मुक्त करना जिसे अवैध रूप से हिरासत में लिया गया हो।
(C) किसी मामले को निचली अदालत से उच्च अदालत में स्थानांतरित करना।
(D) किसी व्यक्ति को सार्वजनिक पद धारण करने से रोकना जिसका वह वैधानिक रूप से हकदार नहीं है।

294. 1980 के दशक से क्षेत्रीय दलों के उदय ने किस युग को जन्म दिया है:
(A) केंद्र में सुदृढ़ एक-दलीय सरकारें।
(B) गठबंधन की राजनीति और अधिक संघीय सौदेबाजी।
(C) सरकार का राष्ट्रपति स्वरूप।
(D) राज्य सरकारों के महत्व में गिरावट।

295. निम्नलिखित प्रमुख संवैधानिक संशोधनों पर विचार करें:
1. 42वां संशोधन अधिनियम
2. 73वां संशोधन अधिनियम
3. प्रथम संशोधन अधिनियम
4. 44वां संशोधन अधिनियम

निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रमिक क्रम दर्शाता है?
(A) 3, 1, 4, 2
(B) 1, 3, 4, 2
(C) 3, 4, 1, 2
(D) 1, 4, 3, 2

296. भारतीय लोकतंत्र में मीडिया के संबंध में एक प्राथमिक चिंता 'पेड न्यूज' है, जो संदर्भित करती है:
(A) किसी विशेष हित को बढ़ावा देने के लिए समाचार लेखों के रूप में छद्म विज्ञापन।
(B) वह समाचार जिसके लिए पाठक को शुल्क देना पड़ता है।
(C) सरकार द्वारा प्रायोजित समाचार बुलेटिन।
(D) वह समाचार जो तथ्य-जांच और सत्यापित हो।

297. सच्चर समिति की रिपोर्ट किस समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए नियुक्त की गई थी?
(A) सिख समुदाय
(B) ईसाई समुदाय
(C) मुस्लिम समुदाय
(D) पारसी समुदाय

298. निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन शामिल हैं - अभिकथन (A) और कारण (R)। उचित विकल्प का चयन करके प्रश्न का उत्तर दें।
अभिकथन (A): भारत के राष्ट्रपति केवल एक नाममात्र के कार्यकारी प्रमुख हैं।
कारण (R): राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से अपनी शक्तियों का प्रयोग करना पड़ता है।
(A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सत्य है लेकिन R असत्य है।

Downloaded from www.pdf.tube

249. निम्नलिखित में से कौन सा किसान आंदोलन का प्रकार नहीं है?
(A) पुनरुद्धारवादी आंदोलन
(B) धार्मिक आंदोलन
(C) औद्योगिक हड़ताल आंदोलन
(D) सामाजिक डकैती

250. चुनावी व्यवहार का समाजशास्त्रीय प्रतिरूप किस भूमिका पर बल देता है:
(A) मतदाताओं की समूह सदस्यता जैसे वर्ग, जाति और धर्म।
(B) दलीय पहचान।
(C) मतदाता द्वारा स्व-हित की तर्कसंगत गणना।
(D) मतदाता की मनोवैज्ञानिक बनावट।

251. भारत के उत्तर-पूर्व में राष्ट्रीय एकीकरण के लिए एक प्रमुख चुनौती रही है:
(A) नदी जल बंटवारे को लेकर संघर्ष।
(B) औद्योगिक प्रदूषण का मुद्दा।
(C) कृषि अर्थव्यवस्था का प्रभुत्व।
(D) अद्वितीय जातीय पहचान के आधार पर उग्रवाद और पृथकता की मांग।

252. भारतीय संविधान में निहित 'सामाजिक न्याय' की अवधारणा का उद्देश्य एक ऐसा समाज बनाना है जहाँ:
(A) सभी की आय पूर्णतः समान हो।
(B) जाति, पंथ, लिंग या धर्म के आधार पर सभी भेदभाव समाप्त कर दिए जाएं।
(C) राज्य उत्पादन के सभी साधनों को नियंत्रित करता हो।
(D) किसी भी निजी संपत्ति की अनुमति न हो।

253. 'विधि की उचित प्रक्रिया' सिद्धांत किस देश के संविधान की विशेषता है:
(A) यूनाइटेड किंगडम
(B) जापान
(C) संयुक्त राज्य अमेरिका
(D) फ्रांस

254. संवैधानिक संशोधन की समीक्षा की प्रक्रिया मुख्य रूप से सर्वोच्च न्यायालय की किस शक्ति के अंतर्गत आती है:
(A) सलाहकार क्षेत्राधिकार
(B) मूल क्षेत्राधिकार
(C) अपीलीय क्षेत्राधिकार
(D) न्यायिक पुनरावलोकन

255. 'धन विधेयक' केवल कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है:
(A) लोकसभा में
(B) राज्यसभा में
(C) दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में
(D) संसद के किसी भी सदन में

256. पुंछी आयोग का गठन 2007 में किस विषय पर विचार करने के लिए किया गया था:
(A) न्यायिक सुधार
(B) चुनावी सुधार
(C) केंद्र-राज्य संबंध
(D) पुलिस सुधार

257. जनहित याचिका किसके द्वारा दायर की जा सकती है:
(A) केवल पीड़ित व्यक्ति द्वारा।
(B) कोई भी सार्वजनिक हित से प्रेरित नागरिक या सामाजिक संगठन।
(C) केवल पीड़ित की ओर से अधिवक्ता।
(D) केवल एक सरकारी अधिकारी।

258. दबाव समूह की तुलना में राजनीतिक दल की विशिष्ट विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है?
(A) यह राष्ट्रीय जीवन के कई पहलुओं को सम्मिलित करने वाला एक व्यापक कार्यक्रम रखता है।
(B) इसका एक औपचारिक संगठन होता है।
(C) यह सरकारी नीति को प्रभावित करना चाहता है।
(D) यह विरोध और पैरवी जैसे तरीकों का उपयोग करता है।

259. चुनावी व्यवहार का 'दलीय पहचान' प्रतिरूप बताता है कि मतदाताओं की पसंद मुख्य रूप से किसके द्वारा निर्धारित होती है:
(A) प्रत्येक चुनाव में उम्मीदवारों की खूबियों का तर्कसंगत मूल्यांकन।
(B) उनके सामाजिक समूहों का प्रभाव।
(C) किसी विशेष राजनीतिक दल के प्रति उनका दीर्घकालिक मनोवैज्ञानिक जुड़ाव।
(D) वर्तमान सरकार का प्रदर्शन।

260. दलित दावे की राजनीति को सबसे अच्छी तरह से इस प्रकार वर्णित किया गया है:
(A) आर्थिक उदारीकरण के लिए एक आंदोलन।
(B) किसी विशिष्ट भाषा को बढ़ावा देने का अभियान।
(C) एक स्वतंत्र राज्य के लिए अलगाववादी आंदोलन।
(D) पहचान, आत्म-सम्मान और राजनीतिक सत्ता में भागीदारी के लिए संघर्ष।

NODIA

261. भारत सरकार अधिनियम, 1935 द्वारा परिकल्पित संघीय योजना अस्तित्व में नहीं आई क्योंकि:
(A) ब्रिटिश सरकार ने प्रस्ताव वापस ले लिया।
(B) द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया।
(C) रियासतों ने संघ में सम्मिलित होने से इनकार कर दिया।
(D) भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया।

262. निम्नलिखित में से कौन सी राज्य के नीति निदेशक तत्वों की विशेषता नहीं है?
(A) वे देश के शासन में मौलिक हैं।
(B) उनका लक्ष्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना

उत्तर (व्याख्या सहित)

1. (B) समाजवादी सिद्धांत
भारतीय संविधान में समाजवादी सिद्धांत सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने पर बल देते हैं। इनका मुख्य लक्ष्य समाज में व्याप्त असमानताओं को समाप्त कर संसाधनों का न्यायसंगत वितरण करना है। राज्य के नीति निदेशक तत्वों में निहित ये सिद्धांत एक समतावादी समाज के निर्माण की संवैधानिक प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं, जिससे प्रत्येक नागरिक का सर्वांगीण और संतुलित विकास संभव हो सके।

2. (A) दस्तावेज़ के मुख्य उद्देश्यों और दर्शन की रुपरेखा तैयार करना
भारतीय संविधान की प्रस्तावना इसके आदर्शों, लक्ष्यों और बुनियादी दर्शन की संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत करती है। यह संविधान निर्माताओं के पवित्र उद्देश्यों और उन मूल्यों को स्पष्ट करती है जिन्हें भारत एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में प्राप्त करना चाहता है। यह न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व जैसे मार्गदर्शक सिद्धांतों की घोषणा करती है, जो संपूर्ण संवैधानिक ढांचे के आधार स्तंभ हैं।

3. (C) यह सरकार के संसदीय स्वरूप की स्थापना करता है।
भारतीय संविधान सरकार की संसदीय प्रणाली स्थापित करता है, जहाँ कार्यपालिका अपनी नीतियों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। यहाँ राष्ट्रपति राज्य का औपचारिक प्रमुख होता है, जबकि प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करती है। यह व्यवस्था उत्तरदायित्व और जवाबदेही के सिद्धांतों पर आधारित है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों और शासन में निरंतर समन्वय सुनिश्चित करती है।

4. (D) आयरलैंड
भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों की अवधारणा आयरलैंड के संविधान से ली गई है। ये तत्व संविधान के भाग 4 में सम्मिलित हैं और शासन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में कार्य करते हैं। इनका प्राथमिक उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना और सामाजिक-आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना है। यद्यपि ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं, फिर भी शासन में इनका स्थान बुनियादी है।

5. (C) संपत्ति का अधिकार
संपत्ति का अधिकार अब भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार नहीं है। पूर्व में अनुच्छेद 31 के तहत यह मौलिक अधिकार था, जिसे 44वें संशोधन अधिनियम (1978) द्वारा हटा दिया गया। वर्तमान में यह भाग 12 के अनुच्छेद 300A के अंतर्गत केवल एक कानूनी अधिकार है। अब राज्य केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से ही किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति अधिग्रहित कर सकता है।

6. (A) P-3, Q-2, R-1, S-4
भारतीय संविधान ने वैश्विक संविधानों से कई महत्वपूर्ण विशेषताएं अपनाई हैं। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रेरित हैं और संसदीय प्रणाली यूनाइटेड किंगडम से ली गई है। नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से प्राप्त हुए हैं, जबकि संघीय योजना की रुपरेखा मुख्य रूप से कनाडा के मॉडल पर आधारित है। यह विविध स्रोतों का संगम संविधान को एक व्यापक और समावेशी दस्तावेज बनाता है।

7. (B) केवल I और III
मौलिक कर्तव्यों को 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में जोड़ा गया था। ये केवल भारतीय नागरिकों पर लागू होते हैं और विदेशियों के लिए बाध्यकारी नहीं हैं। मौलिक अधिकारों के विपरीत ये न्यायोचित नहीं हैं, अर्थात इनके उल्लंघन पर न्यायालय द्वारा दंड नहीं दिया जा सकता। इनका उद्देश्य नागरिकों में राष्ट्रवाद और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना जागृत करना है।

8. (A) संवैधानिक उपचारों का अधिकार
संवैधानिक उपचारों का अधिकार नागरिकों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में सीधे न्यायपालिका की शरण लेने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 32 के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण जैसे आदेश जारी कर सकता है। यह अधिकार सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में न रखा जाए और उसे उचित विधिक प्रक्रिया के माध्यम से त्वरित न्याय प्राप्त हो।

9. (A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
भारतीय संविधान को एक 'जीवंत दस्तावेज' माना जाता है क्योंकि यह समाज की बदलती आवश्यकताओं और समय के अनुसार विकसित होने की क्षमता रखता है। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत इसमें संशोधन की एक व्यवस्थित प्रक्रिया प्रदान की गई है, जो इसे स्थिर होने से बचाती है। यही कारण है कि भारतीय लोकतंत्र विभिन्न चुनौतियों के बावजूद निरंतर प्रभावी बना हुआ है और जन-आकांक्षाओं को पूरा करता है।

10. (B) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना न्यायालयों में सीधे प्रवर्तनीय नहीं है, जिसका अर्थ है कि इसके आधार पर कोई विधिक आदेश जारी नहीं किया जा सकता। हालांकि, यह संविधान के दर्शन और उद्देश्यों को स्पष्ट करने वाला एक महत्वपूर्ण उपकरण है। जहाँ संविधान की भाषा संदिग्ध होती है, न्यायपालिका प्रस्तावना का उपयोग व्याख्या के लिए करती है। दोनों तथ्य सही हैं, परंतु कारण अभिकथन की व्याख्या नहीं करता।

Click Here to Buy book on Amazon

53. (C) भारत के उपराष्ट्रपति को
संविधान के अनुच्छेद 56 के अनुसार, यदि राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले त्यागपत्र देना चाहते हैं, तो उन्हें अपना त्यागपत्र लिखित रूप में उपराष्ट्रपति को संबोधित करना चाहिए। उपराष्ट्रपति इसकी सूचना तत्काल लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं। यह एक औपचारिक प्रक्रिया है जो संवैधानिक पदों के बीच सत्ता के हस्तांतरण को सुनिश्चित करती है। राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति नए राष्ट्रपति के चुनाव तक उनके कार्यों का निर्वहन करते हैं।

54. (B) 2, 4, 1, 3
सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक मामलों का क्रम ए.के. गोपालन मामला (1950) से शुरू होता है। इसके बाद गोलकनाथ मामला (1967) आया, जिसमें संसद की संशोधन शक्तियों पर सीमाएं लगाई गईं। फिर ऐतिहासिक केशवानंद भारती मामला (1973) आया, जिसने 'मूल ढांचे' का सिद्धांत दिया। अंत में, मेनका गांधी मामला (1978) आया, जिसने अनुच्छेद 21 की व्याख्या को व्यापक बनाया। यह क्रम न्यायिक सक्रियता की यात्रा को स्पष्ट करता है।

55. (A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
1992 के 73वें और 74वें संशोधन अधिनियमों ने भारत में स्थानीय स्वशासन की नींव को सशक्त किया। इन संशोधनों ने पंचायती राज संस्थाओं और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया, जिससे वे सरकार के तीसरे स्तर के रूप में स्थापित हुईं। इसका मुख्य उद्देश्य शासन का विकेंद्रीकरण और निर्णय लेने में आम जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना था। इन कदमों ने भारतीय संघवाद को अधिक लोकतांत्रिक और व्यापक बनाया है।

56. (A) स्वायत्तता संवैधानिक ढांचे के भीतर कार्य करती है, जबकि अलगाववाद पृथक होने का प्रयास करता है
राज्य की स्वायत्तता की मांग मुख्य रूप से शक्तियों के पुनर्वितरण और राज्यों को अधिक स्वतंत्रता देने पर केंद्रित होती है, जो संविधान के दायरे में रहती है। इसके विपरीत, अलगाववादी आंदोलन देश की संप्रभुता को चुनौती देते हैं और भारत संघ से पूर्णतः अलग होकर स्वतंत्र राष्ट्र बनाने का प्रयास करते हैं। स्वायत्तता संघीय ढांचे को लचीला बनाने की प्रक्रिया है, जबकि अलगाववाद राष्ट्र के अस्तित्व हेतु सुरक्षा चुनौती है।

57. (C) न्यायिक पुनरावलोकन की शक्तियों को कम करना।
न्यायिक सुधारों का प्राथमिक लक्ष्य न्याय वितरण प्रणाली को अधिक सुलभ, तीव्र और पारदर्शी बनाना है। इसमें न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना, प्रौद्योगिकी का उपयोग और वैकल्पिक विवाद समाधान को बढ़ावा देना शामिल है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्तियों को कम करना सुधार का हिस्सा नहीं हो सकता, क्योंकि यह न्यायपालिका की मूल शक्ति है। वास्तविक सुधार का उद्देश्य न्यायपालिका की दक्षता बढ़ाना है ताकि नागरिकों को समय पर न्याय मिल सके।

58. (A) वन्यजीवों के संरक्षण के लिए अभियान चलाने वाला एक पर्यावरण समूह
प्रचारक या आदर्शवादी दबाव समूह वे होते हैं जो विशिष्ट सार्वजनिक हित या नैतिक मुद्दों को बढ़ावा देने हेतु कार्य करते हैं। पर्यावरण संरक्षण समूह इसका उत्कृष्ट उदाहरण है क्योंकि इसका उद्देश्य समाज के व्यापक कल्याण और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा है। इसके विपरीत, श्रमिक संघ या व्यापार संघ मुख्य रूप से अपने सदस्यों के आर्थिक और व्यावसायिक लाभों हेतु कार्य करते हैं, जो उन्हें स्व-हित समूहों की श्रेणी में रखता है।

59. (D) अन्य सभी उम्मीदवारों की तुलना में सबसे अधिक मत प्राप्त करता है।
भारत में लोकसभा और विधानसभा चुनावों हेतु 'सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय' प्रणाली अपनाई जाती है। इस प्रणाली में वह उम्मीदवार विजयी घोषित होता है जिसे अन्य उम्मीदवारों की तुलना में अधिक वोट मिलते हैं। विजेता हेतु कुल मतों का बहुमत या 50 प्रतिशत प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है। यह एक सरल चुनावी प्रक्रिया है, जो मतदाताओं के लिए समझने में आसान है और विधायी स्थिरता प्रदान करती है।

60. (A) P-3, Q-1, R-4, S-2
बलवंत राय मेहता समिति ने भारत में त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। सरकारिया आयोग का गठन केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों की समीक्षा हेतु किया गया था। तारकुंडे समिति चुनावी सुधारों से संबंधित थी, जिसने मतदान की आयु कम करने के सुझाव दिए थे। मंडल आयोग ने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों हेतु सरकारी नौकरियों में आरक्षण की नीति तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

NODIA

61. (C) भाग IV-A
भारतीय संविधान के भाग IV-A में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है, जिन्हें 42वें संशोधन (1976) द्वारा जोड़ा गया था। प्रारंभ में 10 कर्तव्य थे, परंतु बाद में 86वें संशोधन द्वारा एक और कर्तव्य जोड़ा गया। ये कर्तव्य नागरिकों को राष्ट्र और समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारियों की याद दिलाते हैं। यद्यपि ये न्यायालय द्वारा सीधे प्रवर्तनीय नहीं हैं, फिर भी एक जिम्मेदार नागरिक हेतु ये नैतिक और सामाजिक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।

62. (D) संविधान का मूल ढांचा।
सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती मामले में स्पष्ट किया था कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद की संशोधन शक्ति असीमित नहीं है। संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, बशर्ते वह 'मूल ढांचे' को नष्ट न करे। मूल ढांचे में लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, संघवाद और न्यायपालिका की स्वतंत्रता जैसे सिद्धांत शामिल हैं। यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि संविधान की मूल पहचान और दर्शन को सुरक्षित रखा जाए।

22. (B) कार्यपालिका और विधायी शक्तियों के समन्वय और संलयन की विशेषता वाली प्रणाली।
भारतीय संसदीय प्रणाली की मुख्य विशेषता कार्यपालिका और विधायिका के बीच शक्तियों का संलयन और समन्वय है। इस प्रणाली में कार्यपालिका के सदस्य अनिवार्य रूप से विधायिका का हिस्सा होते हैं और अपने कार्यों हेतु सीधे विधायिका के प्रति जवाबदेह होते हैं। यह व्यवस्था सरकार के संचालन में दक्षता सुनिश्चित करती है और गतिरोध कम करती है। यह सहयोग और सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांतों पर आधारित शासन मॉडल है।

23. (D) लोकसभा के अध्यक्ष
संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत, किसी साधारण विधेयक पर गतिरोध होने की स्थिति में राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। इस बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। यदि अध्यक्ष अनुपस्थित हों, तो उपाध्यक्ष और उनकी अनुपस्थिति में राज्यसभा के उपसभापति अध्यक्षता करते हैं। यह प्रक्रिया विधायी गतिरोध को सुलझाने और महत्वपूर्ण कानूनों को पारित करने के लिए एक महत्वपूर्ण संवैधानिक और विधिक तंत्र है।

24. (A) एकल नागरिकता
एकल नागरिकता भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण एकात्मक विशेषता है। संघीय प्रणालियों में प्रायः दोहरी नागरिकता होती है, परंतु भारत में प्रत्येक व्यक्ति केवल भारतीय नागरिक है, चाहे वह किसी भी राज्य का निवासी हो। यह प्रावधान राष्ट्रीय एकता और अखंडता को सुदृढ़ करने हेतु बनाया गया है। यह सुनिश्चित करता है कि संपूर्ण देश में नागरिकों के अधिकार समान हों और क्षेत्रीय निष्ठा के स्थान पर राष्ट्रीय पहचान प्रमुख रहे।

25. (C) राज्यों के लिए अधिक शक्तियों और वित्तीय संसाधनों की मांग
भारत में केंद्र-राज्य संबंधों के संदर्भ में 'स्वायत्तता' की मांग का तात्पर्य राज्यों द्वारा आंतरिक मामलों में अधिक स्वतंत्रता और वित्तीय संसाधनों की प्राप्ति से है। राज्य तर्क देते हैं कि विकासात्मक कार्यों हेतु उन्हें केंद्र पर निर्भर रहना पड़ता है, जिससे कार्यक्षमता प्रभावित होती है। यह मांग संघीय ढांचे के भीतर ही प्रशासनिक, विधायी और वित्तीय शक्तियों के पुनर्वितरण पर केंद्रित है, न कि अलगाववाद पर।

26. (A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
भारतीय संघवाद को 'अर्ध-संघीय' कहा जाता है क्योंकि इसमें संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की विशेषताएं मौजूद हैं। राज्यों के पास अपनी शक्तियां हैं, परंतु महत्वपूर्ण मामलों में केंद्र का नियंत्रण सर्वोपरि होता है। एकल नागरिकता और आपातकालीन प्रावधान केंद्र को शक्तिशाली बनाते हैं। यह केंद्रीकरण की प्रवृत्ति राष्ट्रीय एकता और स्थिरता बनाए रखने हेतु आवश्यक है, जो अभिकथन के विवरण को स्पष्ट रूप से प्रमाणित करती है।

27. (B) केंद्र-राज्य संबंध
सरकारिया आयोग की नियुक्ति 1983 में केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों की समीक्षा हेतु की गई थी। आयोग ने संघवाद को सशक्त करने, राज्यपाल की भूमिका को निष्पक्ष बनाने और अनुच्छेद 356 के सीमित उपयोग की सिफारिश की थी। इसके सुझावों ने भारत में सहकारी संघवाद की अवधारणा को प्रोत्साहित किया। इसने केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बेहतर समन्वय हेतु एक महत्वपूर्ण और स्थायी आधार तैयार किया।

28. (B) मध्य भारत में नर्मदा बचाओ आंदोलन
नर्मदा बचाओ आंदोलन एक सामाजिक और पर्यावरणीय आंदोलन है, जो विस्थापन और पर्यावरण क्षति के विरुद्ध संघर्ष करता है। इसका उद्देश्य प्रभावित लोगों का पुनर्वास है, न कि स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना। इसके विपरीत, पंजाब का खालिस्तान आंदोलन और नगालैंड के विद्रोह स्पष्ट रूप से अलगाववादी प्रवृत्तियों और स्वायत्तता की मांग से संबंधित थे। नर्मदा आंदोलन संवैधानिक दायरे में रहकर अधिकारों की रक्षा की वकालत करता है।

29. (C) मूल क्षेत्राधिकार
अनुच्छेद 131 के तहत, सर्वोच्च न्यायालय के पास मूल क्षेत्राधिकार होता है, जो उसे केंद्र और राज्यों या विभिन्न राज्यों के बीच विवादों पर निर्णय देने की अनन्य शक्ति प्रदान करता है। ऐसे मामलों की सुनवाई केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही प्रारंभ की जा सकती है। यह शक्ति संघीय ढांचे की स्थिरता और संवैधानिक विवादों का निष्पक्ष समाधान सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक है, जिससे विभिन्न इकाइयों में समन्वय बना रहता है।

30. (D) I, II और III
न्यायिक सक्रियता वह स्थिति है जहाँ न्यायपालिका मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु अपनी पारंपरिक सीमाओं से बाहर निकलकर सक्रिय भूमिका निभाती है। जनहित याचिका इसका महत्वपूर्ण परिणाम है, जिसने आम जनता को न्याय तक सुलभ पहुंच दी है। यद्यपि इसकी आलोचना कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप के रूप में की जाती है, फिर भी यह शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने का एक सशक्त माध्यम है।

31. (A) लोकहित वाद
पी.आई.एल. का पूर्ण रूप 'लोकहित वाद' या जनहित याचिका है। यह भारतीय न्यायपालिका द्वारा विकसित एक नवाचार है जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति जनहित के मामलों के लिए न्यायालय जा सकता है। इसका उद्देश्य वंचित वर्गों को न्याय दिलाना है जो स्वयं न्यायालय तक पहुंचने में असमर्थ हैं। इसने न्याय के नियमों को सरल बनाया है और पर्यावरण संरक्षण तथा मानवाधिकारों की रक्षा में प्रभावी भूमिका निभाई है।

32. (B) राष्ट्रपति
भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इस प्रक्रिया में राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश और कॉलेजियम के वरिष्ठ न्यायाधीशों से परामर्श करते हैं। मुख्य

Downloaded from www.pdf.tube

11. (D) अनुच्छेद 21A
संविधान का अनुच्छेद 21A शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, जिसे 86वें संशोधन अधिनियम (2002) द्वारा मौलिक अधिकार बनाया गया। यह राज्य को 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का निर्देश देता है। यह कदम सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में क्रांतिकारी था, जिसका लक्ष्य प्रत्येक बच्चे को बुनियादी शिक्षा का अवसर प्रदान करना और साक्षरता बढ़ाना है।

12. (B) प्रस्तावना और राज्य के नीति निदेशक तत्व
प्रस्तावना और नीति निदेशक तत्व सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन के प्रमुख संवैधानिक साधन हैं। प्रस्तावना न्याय, समानता और बंधुत्व के लक्ष्यों को निर्धारित करती है, जबकि नीति निदेशक तत्व कल्याणकारी नीतियां बनाने हेतु सरकार को दिशा-निर्देश प्रदान करते हैं। ये प्रावधान एक समतावादी समाज के निर्माण में सहायक हैं, जहाँ संसाधनों का समान वितरण हो और वंचित वर्गों का उत्थान संभव हो सके। यह कल्याणकारी प्रकृति को दर्शाता है।

13. (C) 42वां संशोधन
वर्ष 1976 में पारित 42वें संशोधन अधिनियम को इसकी व्यापकता के कारण 'लघु-संविधान' कहा जाता है। इसने प्रस्तावना, मौलिक अधिकारों और नीति निदेशक तत्वों में व्यापक बदलाव किए। प्रस्तावना में 'समाजवादी', 'धर्मनिरपेक्ष' और 'अखंडता' जैसे शब्द इसी के माध्यम से जोड़े गए थे। इसके द्वारा मौलिक कर्तव्यों की नई श्रेणी भी प्रस्तुत की गई, जिसने संविधान के मूल ढांचे और शासन प्रणाली पर गहरा प्रभाव डाला।

14. (C) केवल I और III
संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। संघीय प्रावधानों में संशोधन हेतु कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। हालांकि, राष्ट्रपति के पास संशोधन विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस भेजने की शक्ति नहीं है, उन्हें सहमति देना अनिवार्य होता है। यह व्यवस्था संघीय ढांचे की सुरक्षा और संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखती है।

15. (A) विधायी अधिनियमों और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच करना
भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ न्यायपालिका की वह शक्ति है जिससे वह विधायी कानूनों और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की समीक्षा करती है। यदि कोई कानून संविधान के प्रावधानों या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय उसे शून्य घोषित कर सकता है। यह शक्ति संविधान की रक्षा करने और कानून के शासन को बनाए रखने में केंद्रीय और निर्णायक भूमिका निभाती है।

16. (B) 2, 1, 3, 4
संविधान निर्माण की घटनाओं का क्रम 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक से शुरु होता है। इसके पश्चात जवाहरलाल नेहरु द्वारा 'उद्देश्य प्रस्ताव' प्रस्तुत किया गया। फिर संविधान का मसौदा तैयार करने हेतु प्रारुप समिति की नियुक्ति की गई। अंत में, लंबी चर्चाओं और संशोधनों के बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान के अंतिम पाठ पर सभा के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए गए, जो ऐतिहासिक क्षण था।

17. (B) नेहरुवादी सिद्धांत - राज्य का उन्मूलन
नेहरुवादी सिद्धांत लोकतांत्रिक समाजवाद, नियोजित अर्थव्यवस्था और आधुनिक राष्ट्र-राज्य के सुदृढ़ीकरण पर आधारित थे, न कि राज्य के उन्मूलन पर। राज्य के उन्मूलन का विचार अराजकतावादी या साम्यवादी विचारधाराओं से संबंधित है। इसके विपरीत, गांधीवादी सिद्धांत ग्राम पंचायतों पर केंद्रित थे और समाजवादी सिद्धांत आर्थिक समानता की वकालत करते थे। उदारवादी सिद्धांत वैज्ञानिक दृष्टिकोण और समान नागरिक संहिता जैसे प्रगतिशील सुधारों पर बल देते हैं।

18. (A) संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य
भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। इसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। मनोनीत सदस्य इस प्रक्रिया में भाग नहीं लेते। यह प्रणाली सुनिश्चित करती है कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से हो और उसमें संपूर्ण देश के जनप्रतिनिधियों की सहभागिता बनी रहे, जिससे पद की गरिमा सुरक्षित रहे।

19. (A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
भारत की संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है, जबकि राष्ट्रपति नाममात्र के कार्यकारी प्रमुख होते हैं। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। सरकार तब तक सत्ता में रहती है जब तक उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है। यह सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि कार्यपालिका विधायी नियंत्रण में रहे, जिससे शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बनी रहती है।

20. (D) विधायी शक्ति
राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति एक महत्वपूर्ण विधायी शक्ति है, जो अनुच्छेद 123 के तहत प्राप्त है। जब संसद सत्र में न हो और तत्काल कार्रवाई आवश्यक हो, तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। इसका प्रभाव संसद द्वारा पारित अधिनियम के समान ही होता है। हालांकि, इसे संसद के आगामी सत्र के छह सप्ताह के भीतर अनुमोदित करना आवश्यक है, अन्यथा यह स्वतः निष्प्रभावी हो जाता है।

21. (B) P-3, Q-2, R-1, S-4
संसदीय शब्दावली में गणपूर्ति का तात्पर्य बैठक के लिए आवश्यक सदस्यों की न्यूनतम संख्या से है। सत्रावसान राष्ट्रपति द्वारा सदन के पूरे सत्र को औपचारिक रूप से समाप्त करने की प्रक्रिया है। स्थगन का उपयोग सदन के कार्य को निश्चित समय के लिए निलंबित करने हेतु होता है। गिलोटिन वह प्रक्रिया है जिसमें समय की कमी के कारण शेष अनुदान मांगों को बिना चर्चा के सीधे मतदान हेतु रखा जाता है।

NODIA

प्रभावी साधन मानी जाती है, जिससे अभिकथन और कारण के बीच संबंध स्थापित होता है।

43. (D) सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति
मंडल आयोग का गठन 1979 में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान हेतु किया गया था। आयोग ने इन वर्गों की स्थिति सुधारने हेतु सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 27 प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश की थी। इन सिफारिशों के कार्यान्वयन ने भारतीय राजनीति में बड़ा सामाजिक बदलाव लाया। इसने पिछड़े वर्गों के सशक्तिकरण और उनकी राजनीतिक भागीदारी को बढ़ाने में अत्यंत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक भूमिका निभाई है।

44. (B) संघवाद
संघवाद भारतीय राजनीति की एक बुनियादी संरचनात्मक विशेषता है, जो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन कर विविधता को समाहित करती है। यह राष्ट्रीय एकीकरण का सशक्त साधन है। इसके विपरीत, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद और जातिवाद नकारात्मक प्रवृत्तियां हैं जो समाज में विभाजन पैदा करती हैं और राष्ट्र की एकता हेतु खतरा उत्पन्न करती हैं। ये संकीर्ण पहचानें अक्सर राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा और सामाजिक वैमनस्य का कारण बनती हैं।

45. (C) अनुसूचित जातियों द्वारा पहचान का दावा और सामाजिक न्याय की मांग
'दलित' राजनीति मुख्य रूप से उन अनुसूचित जातियों के आंदोलनों से संबंधित है जो सामाजिक भेदभाव और उत्पीड़न के विरुद्ध संघर्ष कर रहे हैं। इसका उद्देश्य अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित करना, आत्म-सम्मान प्राप्त करना और सत्ता में उचित भागीदारी सुनिश्चित करना है। यह आंदोलन सामाजिक न्याय के सिद्धांतों पर आधारित है और इसने भारतीय लोकतंत्र को अधिक समावेशी बनाया है। इसके कारण इन वर्गों में अभूतपूर्व राजनीतिक चेतना विकसित हुई है।

46. (D) सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन को सुनिश्चित करना
अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार स्वयं में एक मौलिक अधिकार है, जो अन्य सभी अधिकारों की रक्षा करता है। यह नागरिकों को अधिकारों के उल्लंघन पर सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने की अनुमति देता है। न्यायालय इन अधिकारों को लागू करने हेतु विभिन्न रिट जारी कर सकता है। डॉ. अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा माना था क्योंकि इसके बिना अन्य अधिकार मात्र सैद्धांतिक घोषणाएं बनकर रह जाते।

47. (B) केवल I और II
भारतीय संविधान का निर्माण राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान विकसित लोकतांत्रिक और समतावादी मूल्यों से प्रेरित था। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और अधिकारों के घोषणापत्र जैसे विचार दशकों पूर्व राष्ट्रवादी संघर्षों और नेहरू रिपोर्ट के दौरान ही आकार लेने लगे थे। यह गलत धारणा है कि राष्ट्रवादी नेता संसदीय स्वरूप के विरुद्ध थे; वास्तव में उन्होंने उत्तरदायी शासन हेतु इसी प्रणाली को अपनाया। इन प्रतिबद्धताओं ने संविधान को प्रगतिशील बनाया।

48. (B) संवैधानिक साधनों का उपयोग करते हुए एक समतावादी समाज की ओर शांतिपूर्ण परिवर्तन
संविधान के माध्यम से सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन का तात्पर्य गरीबी, अज्ञानता और असमानता को दूर करना है। यह किसी हिंसक क्रांति के बजाय लोकतांत्रिक और कानूनी प्रक्रियाओं के माध्यम से होने वाला क्रमिक सुधार है। इसका लक्ष्य ऐसी व्यवस्था बनाना है जहाँ प्रत्येक व्यक्ति को विकास के समान अवसर प्राप्त हों और न्याय सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सुलभ हो। नीति निदेशक तत्व इस लक्ष्य प्राप्ति हेतु मार्गदर्शक हैं।

49. (B) 1909 के मार्ले-मिंटो सुधार
1909 के भारतीय परिषद अधिनियम ने पहली बार ब्रिटिश भारत में मुसलमानों के लिए 'पृथक निर्वाचक मंडल' की शुरुआत की। इस प्रावधान के तहत मुस्लिम उम्मीदवारों का चुनाव केवल मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। इस कदम ने सांप्रदायिक राजनीति के बीज बोए और भविष्य में देश के विभाजन की नींव रखी। इसे प्रायः 'वैध सांप्रदायिकता' की शुरुआत माना जाता है, जिसने भारतीय राष्ट्रवाद के धर्मनिरपेक्ष ढांचे को क्षति पहुंचाई।

50. (A) राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं।
भारतीय संसदीय प्रणाली में मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, न कि राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति राष्ट्र का औपचारिक प्रमुख होता है और उसकी शक्तियां प्रायः सलाहकार प्रकृति की होती हैं। यद्यपि राष्ट्रपति रक्षा बलों के सर्वोच्च सेनापति होते हैं, परंतु वास्तविक कार्यकारी निर्णय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही लिए जाते हैं। राष्ट्रपति का मुख्य कार्य संवैधानिक मर्यादाओं की रक्षा और शासन के सुचारु संचालन को सुनिश्चित करना है।

51. (C) सामूहिक उत्तरदायित्व
भारतीय संसदीय प्रणाली सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर आधारित है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 75 में है। इसका अर्थ है कि पूरी मंत्रिपरिषद अपने कार्यों और निर्णयों हेतु सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यदि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए, तो पूरे मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि सरकार एक इकाई के रूप में कार्य करे और संसद के प्रति जवाबदेह रहे।

52. (D) विधायिका के दो सदनों का अस्तित्व।
द्विसदनीयता का अर्थ है कि देश की विधायिका में दो सदन होते हैं। भारत में संसद के दो सदन हैं: लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा प्रत्यक्ष रूप से जनता का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि राज्यसभा राज्यों के हितों का प्रतिनिधित्व करती है। यह व्यवस्था कानून निर्माण में संतुलन बनाने, महत्वपूर्ण विधेयकों पर पुनर्विचार करने और विभिन्न दृष्टिकोणों को स्थान देने में सहायक होती है। कुछ राज्यों में भी यह प्रणाली मौजूद है।

Click Here to Buy book on Amazon

में वी.वी.पी.ए.टी. के जुड़ने से मतदाता की संतुष्टि और चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता में और अधिक वृद्धि हुई है।

94. (C) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।
दबाव समूह और राजनीतिक दल अलग निकाय हैं, यद्यपि दोनों राजनीति को प्रभावित करते हैं। राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं और सरकार बनाने का लक्ष्य रखते हैं, जबकि दबाव समूह सत्ता में आए बिना विशिष्ट नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। राजनीतिक दलों का एजेंडा व्यापक होता है, जबकि दबाव समूह अक्सर एक ही मुद्दे या विशेष वर्ग के हितों तक सीमित रहते हैं। दबाव समूह लोकतंत्र में सरकार पर निरंतर निगरानी रखने में सहायक होते हैं।

95. (A) मिनर्वा मिल्स मामला
1980 के मिनर्वा मिल्स मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि संविधान मौलिक अधिकारों और नीति निदेशक तत्वों के बीच संतुलन पर आधारित है। न्यायालय ने इन्हें 'एक ही रथ के दो पहिये' कहा, जिसका अर्थ है कि एक हेतु दूसरे का बलिदान नहीं दिया जा सकता। यह निर्णय सामाजिक विकास और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच आदर्श सामंजस्य स्थापित करता है। इसने स्पष्ट किया कि संविधान के लक्ष्यों हेतु दोनों भागों का सुसंगत कार्यान्वयन आवश्यक है।

96. (D) I, II और III
प्रधानमंत्री की शक्तियां व्यापक हैं और वे मंत्रिपरिषद के केंद्र बिंदु हैं। वे नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, जो देश के विकास की दिशा निर्धारित करता है। मंत्रियों की नियुक्ति और विभागों का आवंटन उन्हीं की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त, वे राजनीतिक स्थिति के आधार पर राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने और नए चुनाव की सिफारिश करने की शक्ति रखते हैं। ये भूमिकाएं प्रधानमंत्री को भारतीय व्यवस्था में सबसे प्रभावशाली पद बनाती हैं।

97. (B) कानून बनाने के लिए राज्य सूचियों का अस्तित्व
राज्य सूचियों का अस्तित्व संविधान की एक अनिवार्य संघीय विशेषता है, जो राज्यों को विशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की स्वायत्तता प्रदान करती है। यह शक्तियों के विकेंद्रीकरण का प्रतीक है। इसके विपरीत, राज्यपाल का पद और आपातकालीन प्रावधान सुदृढ़ एकात्मक प्रवृत्तियों के उदाहरण हैं क्योंकि ये केंद्र को राज्यों पर नियंत्रण प्रदान करते हैं। संघीय ढांचे में इन एकात्मक विशेषताओं का समावेश राष्ट्रीय अखंडता को संकट के समय सुरक्षित रखने हेतु किया गया है।

98. (A) न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण।
कॉलेजियम प्रणाली उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की एक प्रक्रिया है। यह प्रणाली स्वयं न्यायपालिका द्वारा विकसित की गई है, जिसका उल्लेख मूल संविधान में नहीं था। इसमें मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीशों का समूह शामिल होता है। वे सरकार को न्यायाधीशों के नाम प्रस्तावित करते हैं। यह व्यवस्था न्यायिक स्वतंत्रता को बनाए रखने हेतु महत्वपूर्ण मानी जाती है, यद्यपि पारदर्शिता के मुद्दों पर इसकी अक्सर चर्चा होती रहती है।

99. (C) मतदाताओं की पसंद के पीछे के प्रतिरूप और प्रेरणाएं।
चुनावी व्यवहार का अध्ययन इस बात का विश्लेषण करता है कि मतदाता अपना निर्णय किन आधारों पर लेते हैं। इसमें जाति, धर्म और राजनीतिक विचारधारा जैसे सामाजिक-मनोवैज्ञानिक कारकों की भूमिका जांची जाती है। इसके साथ ही यह चुनाव प्रचार और उम्मीदवारों के प्रदर्शन के प्रति जनता की प्रतिक्रिया का सूक्ष्म अध्ययन करता है। यह शोध राजनीतिक दलों को रणनीतियां बनाने और लोकतंत्र में जनमत के बदलते रुझानों को समझने में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

100. (D) राष्ट्रीय हितों के बजाय अपने धार्मिक समुदाय के प्रति निष्ठा।
सांप्रदायिकता एक ऐसी विचारधारा है जो समाज को धार्मिक आधार पर विभाजित करती है। राष्ट्र-निर्माण में यह बड़ी बाधा है क्योंकि यह नागरिकों की वफादारी को राष्ट्र के बजाय धर्म के प्रति केंद्रित कर देती है, जिससे सामाजिक वैमनस्य उत्पन्न हो सकता है। यह साझा राष्ट्रीय पहचान और धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों को कमजोर करती है। सांप्रदायिकता के कारण देश की एकता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जो अंततः लोकतांत्रिक स्थिरता के लिए संकट पैदा करता है।

101. (C) जवाहरलाल नेहरू
13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में 'उद्देश्य प्रस्ताव' पेश किया था। इस प्रस्ताव ने भावी संविधान के बुनियादी ढांचे और दर्शन को परिभाषित किया, जिसमें भारत को संप्रभु गणराज्य बनाने का संकल्प था। इसने समानता और सामाजिक न्याय के उन मूल्यों को रेखांकित किया जो राष्ट्र निर्माण का आधार बने। यही प्रस्ताव भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आधार बना, जो आज भी हमारे मार्गदर्शक सिद्धांतों का सबसे पवित्र और संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करता है।

102. (B) संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया।
भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया इसे कठोरता और लचीलेपन का अनूठा मिश्रण बनाती है। कुछ प्रावधानों को साधारण बहुमत से बदला जा सकता है, जो लचीलेपन को दर्शाता है। महत्वपूर्ण संघीय परिवर्तनों हेतु विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है, जो इसकी कठोरता का प्रतीक है। यह संतुलन सुनिश्चित करता है कि संविधान बदलती जरूरतों के अनुसार विकसित हो सके, परंतु इसकी मूल पवित्रता और संघीय ढांचे के साथ मनमाना परिवर्तन न किया जा सके।

103. (D) अनुच्छेद 20
अनुच्छेद 20 नागरिकों को अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में महत्वपूर्ण संरक्षण प्रदान करता है। पहला, किसी व्यक्ति को केवल उस कानून के उल्लंघन हेतु दंडित किया जा सकता है जो अपराध के समय लागू था। दूसरा, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध हेतु दो बार दंडित नहीं किया जा सकता। तीसरा, किसी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध गवाही देने हेतु बाध्य

NODIA

63. (A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
संसदीय लोकतंत्र में मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है कि सभी मंत्री सरकार के निर्णयों हेतु संयुक्त रूप से जिम्मेदार होते हैं। यदि लोकसभा किसी एक मंत्री के विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देती है, तो इसे पूरी सरकार के प्रति अविश्वास माना जाता है और पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि कार्यपालिका संसद के प्रति जवाबदेह बनी रहे।

64. (B) उन्हें छह महीने के भीतर संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना होगा।
भारतीय संविधान के अनुसार, राष्ट्रपति किसी भी ऐसे व्यक्ति को मंत्री नियुक्त कर सकते हैं जो संसद का सदस्य नहीं है। हालांकि, ऐसे व्यक्ति हेतु यह अनिवार्य है कि वह नियुक्ति की तिथि से छह महीने के भीतर लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हो जाए। यदि वह इस समय सीमा में सदस्यता प्राप्त करने में विफल रहता है, तो उसे मंत्री पद छोड़ना पड़ता है। यह प्रावधान विशेषज्ञता को अवसर देता है।

65. (B) सातवीं अनुसूची
संविधान की सातवीं अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण का प्रावधान करती है। इसमें तीन सूचियाँ हैं: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पर संसद और राज्य सूची पर विधानमंडल कानून बनाते हैं। समवर्ती सूची पर दोनों कानून बना सकते हैं। यह व्यवस्था भारतीय संघीय ढांचे को मजबूती प्रदान करती है और विभिन्न स्तरों पर सरकार के कार्यों में स्पष्टता और शासन में व्यवस्था सुनिश्चित करती है।

66. (D) I, II और III
सर्वोच्च न्यायालय देश की न्यायिक व्यवस्था के शीर्ष पर स्थित है और अंतिम अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य करता है। इसके पास न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है, जिससे यह संविधान की रक्षा करता है। इसका मूल क्षेत्राधिकार अनन्य है, जहाँ केंद्र और राज्यों के विवादों की सुनवाई होती है। यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक भी है। ये शक्तियां सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय लोकतंत्र का अत्यंत शक्तिशाली और महत्वपूर्ण स्तंभ बनाती हैं।

67. (C) सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की शुरुआत
भारत सरकार अधिनियम 1935 संवैधानिक इतिहास में महत्वपूर्ण था, परंतु इसने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की शुरुआत नहीं की थी। इस अधिनियम ने मताधिकार का विस्तार किया, परंतु वह संपत्ति, शिक्षा और कर भुगतान की शर्तों पर आधारित था। इसने अखिल भारतीय संघ, केंद्र में द्वैध शासन और प्रांतीय स्वायत्तता जैसे प्रावधान प्रस्तुत किए थे। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार स्वतंत्रता के बाद केवल 1950 के संविधान द्वारा ही पूर्णतः लागू हो सका।

68. (D) एम. एन. राय
भारत हेतु एक स्वतंत्र संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम 1934 में वामपंथी नेता एम. एन. राय द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1935 में आधिकारिक तौर पर संविधान सभा की मांग की। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यह मांग और तेज हुई, जिसे अंततः 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के तहत स्वीकार किया गया। एम. एन. राय का यह सुझाव भारतीय लोकतंत्र के निर्माण की दिशा में दूरदर्शी कदम था।

69. (C) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।
संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार असीमित नहीं हैं। यद्यपि ये नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं, परंतु राज्य सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और राष्ट्र की सुरक्षा हेतु इन पर 'उचित प्रतिबंध' लगा सकता है। यह व्यवस्था व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक उत्तरदायित्व के बीच संतुलन बनाने हेतु आवश्यक है। अधिकारों का प्रयोग इस प्रकार होना चाहिए कि वह समाज के व्यापक हितों को क्षति न पहुँचाए, जो स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है।

NODIA

70. (B) अनुच्छेद 21
अनुच्छेद 21 संविधान का अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो घोषणा करता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना वंचित नहीं किया जाएगा। न्यायपालिका ने इसकी व्याख्या व्यापक रूप से की है, जिसमें गरिमापूर्ण जीवन, निजता और शिक्षा का अधिकार शामिल है। यह अधिकार नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है और राज्य की मनमानी कार्रवाइयों के विरुद्ध सशक्त सुरक्षा कवच प्रदान करता है।

71. (D) संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के स्थान पर विधिक अधिकार बना दिया।
1978 के 44वें संशोधन अधिनियम ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया। इसके माध्यम से अनुच्छेद 31 को निरस्त कर संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300A के तहत एक कानूनी अधिकार बनाया गया। इसका उद्देश्य सामाजिक-आर्थिक न्याय को प्रभावी ढंग से लागू करना था। इस संशोधन ने आपातकाल के दौरान की गई ज्यादतियों को सुधारने और लोकतांत्रिक सुरक्षा उपायों को पुनः स्थापित करने का कार्य भी किया।

72. (A) विधायिका के प्रति कार्यपालिका की उत्तरदायित्व।
भारतीय संसदीय प्रणाली का केंद्रीय पहलू कार्यपालिका का विधायिका के प्रति निरंतर उत्तरदायित्व है। इसका अर्थ है कि सरकार को अपने प्रत्येक निर्णय हेतु संसद, विशेषकर लोकसभा को जवाब देना पड़ता है। यह उत्तरदायित्व प्रश्न काल, चर्चाओं और अविश्वास प्रस्ताव जैसे माध्यमों से सुनिश्चित होता है। यदि सरकार संसद का विश्वास खो देती है, तो वह सत्ता में नहीं रह सकती। यह सिद्धांत तानाशाही को रोकता है और शासन में पारदर्शिता लाता है।

73. (C) केंद्रीय संसद में
भारतीय संविधान के तहत, उन विषयों पर कानून बनाने की शक्ति जो किसी भी सूची में स्पष्ट नहीं हैं, केंद्रीय संसद में निहित है। इन्हें 'अवशिष्ट शक्तियां' कहा जाता है, जिनका उल्लेख अनुच्छेद 248 में है। यह व्यवस्था भारतीय संघ के सुदृढ़ केंद्रीय

झुकाव को दर्शाती है, जो कनाडा के संविधान से प्रेरित है। यह सुनिश्चित करता है कि भविष्य में उभरने वाले नए विषयों पर नियंत्रण और कानून निर्माण की शक्ति केंद्र के पास रहे।

74. (A) अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन का दायरा।
एस.आर. बोम्मई मामला केंद्र-राज्य संबंधों और अनुच्छेद 356 के उपयोग के संदर्भ में ऐतिहासिक था। सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि राष्ट्रपति शासन की घोषणा न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन है और सरकार के बहुमत का परीक्षण विधानसभा के पटल पर ही होना चाहिए। इस निर्णय ने केंद्र द्वारा राज्य सरकारों को मनमाने ढंग से बर्खास्त करने पर अंकुश लगाया और भारतीय संघवाद की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

75. (D) सोशल मीडिया के माध्यम से असत्यापित जानकारी फैलाना।
जनमत को प्रभावित करने के औपचारिक साधनों में व्यवस्थित और उत्तरदायी माध्यम शामिल हैं, जैसे राजनीतिक घोषणापत्र और आधिकारिक प्रकाशन। ये स्रोत तथ्यों और सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। इसके विपरीत, सोशल मीडिया पर असत्यापित जानकारी या झूठी खबरें फैलाना एक अनौपचारिक और हानिकारक साधन है, जो जनमत को गुमराह करता है। यह लोकतांत्रिक चर्चाओं की गुणवत्ता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है और समाज में भ्रम पैदा करता है।

76. (B) जाति
भारतीय सामाजिक परिदृश्य में 'वर्ग' की अवधारणा अक्सर 'जाति' के साथ गहराई से जुड़ी पाई जाती है। ऐतिहासिक रूप से आर्थिक और सामाजिक स्थिति का जाति के साथ गहरा संबंध रहा है, जहाँ वंचित जातियों के लोग प्रायः आर्थिक रूप से भी पिछड़े रहे हैं। इस कारण राजनीतिक लामबंदी और सामाजिक न्याय की मांगें अक्सर जाति और वर्ग दोनों को समाहित करती हैं। आरक्षण जैसी नीतियां भी इसी अंतःसंबंध को संबोधित करती हैं।

77. (C) यह चुनावी प्रक्रिया के प्रशासन के लिए उत्तरदायी एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है।
भारत का निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है, जिसे निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसकी स्वतंत्रता हेतु मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें संविधान द्वारा सुरक्षित हैं। यह आयोग केवल सलाहकार निकाय नहीं है, बल्कि चुनाव प्रक्रिया पर इसका व्यापक प्रशासनिक नियंत्रण होता है। यह मतदाता सूची तैयार करने से लेकर परिणामों की घोषणा तक की समस्त गतिविधियों का संचालन सुचारु रूप से करता है।

78. (D) द्रविड़ मुनेत्र कड़गम
द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डी.एम.के.) एक प्रमुख क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, जिसका आधार मुख्य रूप से तमिलनाडु राज्य में है। यह दल क्षेत्रीय पहचान, भाषाई गौरव और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों पर केंद्रित है। इसके विपरीत, कांग्रेस और भाजपा जैसे दल राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक उपस्थिति रखते हैं। क्षेत्रीय दल किसी विशेष राज्य की विशिष्ट समस्याओं और आकांक्षाओं को राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी ढंग से उठाने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

79. (A) सार्वजनिक कर्तव्यों को लागू करने और अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका द्वारा सक्रिय भूमिका निभाना।
न्यायिक सक्रियता का तात्पर्य न्यायपालिका द्वारा अपनी पारंपरिक भूमिका से आगे बढ़कर नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और सार्वजनिक नीति में हस्तक्षेप करना है। यह तब होता है जब कार्यपालिका या विधायिका अपने संवैधानिक कर्तव्यों में विफल रहती हैं। जनहित याचिकाओं के माध्यम से न्यायपालिका पर्यावरण और मानवाधिकार जैसे मुद्दों पर निर्देश जारी करती है। यह लोकतंत्र में 'नियंत्रण और संतुलन' के सिद्धांत को सुदृढ़ करती है और शासन में पारदर्शिता लाती है।

80. (B) अनुच्छेद 32 - संपत्ति का अधिकार
अनुच्छेद 32 का संबंध 'संवैधानिक उपचारों के अधिकार' से है, जिसे डॉ. अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। यह नागरिकों को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है। संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है; इसे 1978 में अनुच्छेद 300A के अंतर्गत विधिक अधिकार बना दिया गया था। अन्य युग्म सही हैं, जैसे अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता उन्मूलन और अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्यों के बारे में हैं।

81. (B) राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष
भारत की वरीयता सूची में राष्ट्रपति सर्वोच्च पद पर होते हैं, क्योंकि वे राष्ट्र के प्रमुख हैं। उनके बाद उपराष्ट्रपति का स्थान आता है, जो देश के दूसरे नागरिक माने जाते हैं। तीसरे स्थान पर प्रधानमंत्री होते हैं, जो सरकार के वास्तविक कार्यकारी प्रमुख हैं। राज्यों के राज्यपाल और पूर्व राष्ट्रपतियों के बाद लोकसभा अध्यक्ष और मुख्य न्यायाधीश संयुक्त रूप से महत्वपूर्ण स्थान पर आते हैं। यह व्यवस्था विभिन्न संवैधानिक पदों की गरिमा को दर्शाती है।

82. (A) 42वां संशोधन अधिनियम
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संशोधन किया गया है, जो 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा हुआ था। इसके माध्यम से प्रस्तावना में 'समाजवादी', 'धर्मनिरपेक्ष' और 'अखंडता' जैसे तीन महत्वपूर्ण शब्द जोड़े गए थे। यह संशोधन आपातकाल के दौरान किया गया था जिसका उद्देश्य संवैधानिक लक्ष्यों को अधिक व्यापक बनाना था। यह दर्शाता है कि प्रस्तावना संविधान का गतिशील हिस्सा है जिसे मूल सिद्धांतों के साथ संशोधित किया जा सकता है।

83. (C) डॉ. बी.आर. अंबेडकर
डॉ. बी.आर. अंबेडकर संविधान सभा की 'प्रारूप समिति' के अध्यक्ष थे। इस समिति की जिम्मेदारी संविधान का मसौदा तैयार करना और उसे अंतिम रूप देना था। उनके गहन विधिक ज्ञान के कारण उन्हें 'भारतीय संविधान के जनक' के रूप में जाना जाता है। उन्होंने विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन किया और भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप एक व्यापक और

Downloaded from www.pdf.tube

न्यायसंगत दस्तावेज़ तैयार करने में नेतृत्व प्रदान किया। उनके योगदान ने संविधान को समावेशी बनाया।

84. (D) ब्रिटेन
अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त 'कानून के समक्ष समानता' की अवधारणा ब्रिटिश संवैधानिक परंपरा से ली गई है। इसका अर्थ है कि देश के भीतर कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है और प्रत्येक व्यक्ति साधारण अदालतों के कानून के अधीन समान माना जाएगा। यह 'विधि के शासन' का पहलू है जिसका उद्देश्य विशेषाधिकारों को समाप्त करना है। इसके साथ ही 'कानूनों का समान संरक्षण' अमेरिकी संविधान से लिया गया है, जो समान व्यवहार पर बल देता है।

85. (C) ग्राम पंचायतों को स्वशासन की इकाइयों के रूप में संगठित करना।
अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायतों का गठन गांधीवादी विचारधारा पर आधारित एक प्रमुख नीति निदेशक तत्व है। महात्मा गांधी का मानना था कि वास्तविक लोकतंत्र तभी सफल हो सकता है जब गांवों को स्वशासित बनाया जाए। यह सिद्धांत सत्ता के विकेंद्रीकरण और स्थानीय स्तर पर जनता की भागीदारी को बढ़ावा देने पर बल देता है। इसी लक्ष्य हेतु 1992 में 73वां संशोधन अधिनियम पारित कर पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी।

86. (A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
राज्यसभा को भारतीय संसद का स्थायी सदन माना जाता है क्योंकि इसे कभी भी पूर्णतः भंग नहीं किया जा सकता। इसके सदस्यों का कार्यकाल छह वर्ष होता है और एक-तिहाई सदस्य प्रत्येक दो वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। यह निरंतरता सुनिश्चित करती है कि विधायी कार्य बिना किसी रुकावट के चलते रहें, भले ही लोकसभा भंग हो गई हो। अतः कारण, अभिकथन के स्थायी सदन होने के तर्क की सटीक और तार्किक व्याख्या करता है।

87. (D) अविश्वास प्रस्ताव
अविश्वास प्रस्ताव संसदीय प्रणाली का एक शक्तिशाली उपकरण है जिसे केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। यह प्रस्ताव सरकार के बहुमत का परीक्षण करने हेतु लाया जाता है। यदि यह प्रस्ताव सदन में बहुमत से पारित हो जाता है, तो सरकार को अनिवार्य रूप से त्यागपत्र देना पड़ता है। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि कार्यपालिका हमेशा निर्वाचित प्रतिनिधियों के समर्थन पर टिकी रहे। यह लोकतांत्रिक नियंत्रण और जवाबदेही बनाए रखने का एक प्रमुख साधन है।

88. (A) सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद।
हाल के वर्षों में भारत में केंद्र-राज्य संबंध 'सहकारी' और 'प्रतिस्पर्धी' संघवाद की दिशा में विकसित हुए हैं। सहकारी संघवाद में केंद्र और राज्य साझा लक्ष्यों हेतु मिलकर कार्य करते हैं, जबकि प्रतिस्पर्धी संघवाद में राज्य निवेश हेतु आपस में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा करते हैं। नीति आयोग ने इस नई प्रवृत्ति को प्रोत्साहित किया है। यह बदलाव राज्यों को विकास की प्रक्रिया में अधिक सक्रिय भागीदार बनाने की दिशा में एक सकारात्मक और प्रभावी कदम है।

89. (C) संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया अत्यंत सुरक्षित है, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान है। उन्हें केवल 'सिद्ध कदाचार' या 'अक्षमता' के आधार पर हटाया जा सकता है। इसके लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होना आवश्यक है। संसद की इस सिफारिश के बाद ही राष्ट्रपति उन्हें पद से हटाने का आदेश जारी कर सकते हैं। यह कठिन प्रक्रिया न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित रखने हेतु बनाई गई है।

90. (A) P-3, Q-1, R-4, S-2
न्यायालयों द्वारा जारी रिटों के विशिष्ट अर्थ हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ है व्यक्ति को सशरीर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना। परमादेश एक आधिकारिक आदेश है जिसका अर्थ है 'हम आज्ञा देते हैं'। उत्प्रेषण का उपयोग निचली अदालत के रिकॉर्ड को समीक्षा हेतु ऊपर मंगाने हेतु किया जाता है। अधिकार-पृच्छा यह प्रश्न करती है कि कोई व्यक्ति 'किस अधिकार से' किसी सार्वजनिक पद पर आसीन है, जिससे पद के दुरुपयोग को प्रभावी ढंग से रोका जा सके।

91. (D) राजनीतिक संस्थाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व।
भारतीय राजनीति में लिंग का मुद्दा मुख्य रूप से निर्णय लेने वाली संस्थाओं में महिलाओं की कम भागीदारी से संबंधित है। यद्यपि पंचायतों में सीटें आरक्षित हैं, परंतु संसद में महिला आरक्षण विधेयक लंबे समय तक चर्चा का विषय रहा है। इसका उद्देश्य न केवल महिलाओं की संख्या बढ़ाना है, बल्कि नीति निर्माण में लिंग-संवेदी दृष्टिकोण को शामिल करना है। यह महिलाओं के सामाजिक और राजनीतिक सशक्तिकरण हेतु एक आवश्यक कदम और लोकतांत्रिक सुधार माना जाता है।

92. (B) विविधता का सम्मान करते हुए एक साझा पहचान और साझा नागरिकता को बढ़ावा देना।
भारत जैसे बहुलवादी समाज में राष्ट्र-निर्माण एक जटिल प्रक्रिया है जहाँ विभिन्न संस्कृतियों के बीच सामंजस्य आवश्यक है। इसका उद्देश्य किसी एक संस्कृति को थोपना नहीं, बल्कि 'विविधता में एकता' को साकार करना है। एक साझा राष्ट्रीय पहचान विकसित करना महत्वपूर्ण है जो क्षेत्रीय वफादारियों से ऊपर हो। यह तभी संभव है जब सभी समुदायों को समान अधिकार और अवसर प्राप्त हों, जिससे देश के प्रति उनमें सुरक्षा और अपनत्व की भावना जागृत हो सके।

93. (C) इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की शुरुआत।
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ई.वी.एम.) की शुरुआत एक युगांतरकारी चुनावी सुधार है जिसने चुनाव प्रक्रिया को अधिक कुशल और पारदर्शी बनाया है। इसने मतपत्रों की गणना में होने वाली कठिनाइयों और समय की बर्बादी को समाप्त किया है। इसके साथ ही, ई.वी.एम. ने फर्जी मतदान और बूथ कैप्चरिंग जैसी समस्याओं को कम करने में सहायता की है। हाल के वर्षों

NODIA

न्यायाधीश की नियुक्ति हेतु प्रायः सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश का चयन किया जाता है। यह नियुक्ति प्रक्रिया न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने हेतु संवैधानिक रूप से निर्धारित है, जिससे कानून की सर्वोच्चता बनी रहे और राजनीतिक हस्तक्षेप न्यूनतम रहे।

33. (B) यह संवैधानिक साधनों के माध्यम से राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना चाहता है।
राजनीतिक दल समान विचारधारा वाले लोगों का संगठित समूह होता है जो चुनावों के माध्यम से सत्ता प्राप्त करने का प्रयास करता है। इनका प्राथमिक उद्देश्य सरकार बनाना और नीतियों को प्रभावित करना है। ये दल जनमत तैयार करते हैं और नागरिकों एवं शासन के बीच सेतु का कार्य करते हैं। दबाव समूहों के विपरीत, राजनीतिक दल सीधे चुनावी प्रक्रिया में भाग लेते हैं और सार्वजनिक नीति पर व्यापक दृष्टिकोण रखते हैं।

34. (A) 1, 2, 3, 4
भारत के प्रधानमंत्रियों का सही कालानुक्रमिक क्रम जवाहरलाल नेहरू से शुरू होता है। उनके बाद लाल बहादुर शास्त्री ने पदभार संभाला। शास्त्री जी के आकस्मिक निधन के पश्चात इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनीं। अंत में, 1977 में आपातकाल के बाद हुए चुनावों में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में पहली गैर-कांग्रेसी सरकार बनी। यह क्रम भारत के राजनीतिक इतिहास के विभिन्न चरणों और लोकतांत्रिक विकास की क्रमिक यात्रा को दर्शाता है।

35. (B) एक संगठन जो सत्ता प्राप्त करने की कोशिश किए बिना सरकारी नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करता है।
दबाव समूह उन लोगों के संगठित समूह होते हैं जो अपने विशेष हितों की रक्षा हेतु सरकार पर दबाव डालते हैं। ये समूह प्रत्यक्ष रूप से चुनाव नहीं लड़ते और न ही इनका उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना होता है। इसके बजाय, वे प्रचार, धरना और प्रदर्शन जैसे माध्यमों से सार्वजनिक नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। ये लोकतंत्र में विभिन्न समूहों के हितों की अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण माध्यम हैं।

36. (A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
लोकतंत्र में जनमत एक शक्तिशाली शक्ति है जो सरकार को जनता की इच्छाओं के प्रति उत्तरदायी और संवेदनशील बनाए रखती है। सरकार की सफलता अक्सर सार्वजनिक राय के सम्मान पर निर्भर करती है। इस जनमत को आकार देने और जानकारी फैलाने में मीडिया एक अनिवार्य माध्यम के रूप में कार्य करता है। मीडिया की स्वतंत्रता और निष्पक्षता एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अपरिहार्य है, जो नागरिकों को जागरूक बनाती है।

37. (C) भूमि अधिकार और किसानों का शोषण
1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी में शुरू हुआ विद्रोह मुख्य रूप से भूमिहीन किसानों के अधिकारों और जमींदारों द्वारा शोषण के विरुद्ध था। यह आंदोलन भूमि पुनर्वितरण और ग्रामीण गरीबों के सशक्तिकरण पर केंद्रित था। इसने भारत में उग्रवादी वामपंथी विचारधारा को जन्म दिया, जिसे नक्सलवाद कहा गया। यद्यपि इसका उद्देश्य सामाजिक न्याय था, परंतु इसने सशस्त्र संघर्ष का मार्ग अपनाया, जो आंतरिक सुरक्षा हेतु चुनौती बन गया।

38. (B) भारत का निर्वाचन आयोग
भारत का निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है, जिसे अनुच्छेद 324 के तहत संसद, विधानसभा और राष्ट्रपति पदों के चुनाव आयोजित करने की शक्ति प्राप्त है। आयोग मतदाता सूची तैयार करने, चुनाव कार्यक्रम घोषित करने और आचार संहिता लागू करने हेतु उत्तरदायी है। इसकी निष्पक्षता हेतु इसे कार्यकारी नियंत्रण से मुक्त रखा गया है। यह स्वतंत्र और पारदर्शी चुनावी प्रक्रिया की आधारशिला है, जो लोकतंत्र को सुदृढ़ करती है।

39. (B) P-3, Q-1, R-4, S-2
चुनावी व्यवहार के अंतर्गत उन कारकों का अध्ययन किया जाता है जो मतदान के प्रतिरूप को निर्धारित करते हैं। चुनावी सुधार का तात्पर्य चुनाव प्रक्रिया को अधिक निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के उपायों से है। जनमत किसी सार्वजनिक मुद्दे पर लोगों के सामूहिक दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है। दबाव समूह ऐसे संगठन हैं जो सत्ता प्राप्त किए बिना अपने हितों की पूर्ति हेतु सरकार की नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं।

40. (A) जाति, वर्ग और धर्म सहित विभिन्न कारकों की एक जटिल अंतःक्रिया
भारत में चुनावी व्यवहार किसी एक कारक से नहीं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक तत्वों के मिश्रण से निर्धारित होता है। मतदाता प्रायः जातिगत पहचान, धार्मिक संबद्धता और आर्थिक वर्ग से प्रभावित होते हैं। इसके साथ ही उम्मीदवारों की छवि, विकास के मुद्दे और राष्ट्रीय लहर भी निर्णायक भूमिका निभाती है। यह जटिल अंतःक्रिया मतदाताओं के निर्णय लेने की प्रक्रिया को आकार देती है, जो विभिन्न चुनावों में अलग-अलग प्रकट होती है।

41. (C) 52वां संशोधन अधिनियम
दल-बदल विरोधी कानून को 1985 के 52वें संशोधन अधिनियम द्वारा लागू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य राजनीतिक लाभ हेतु दल बदलने की अनैतिक प्रवृत्ति को रोकना था, जिससे अस्थिरता पैदा होती थी। इस कानून के तहत संसद या विधानसभा सदस्यों को अयोग्य ठहराने के प्रावधान हैं। इसे संविधान की दसवीं अनुसूची में शामिल किया गया है, जो राजनीतिक शुचिता और दलीय अनुशासन को बढ़ावा देने का कार्य करता है।

42. (A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
भारतीय राजनीति में जाति एक बुनियादी वास्तविकता है, जो चुनावी परिणामों को गहराई से प्रभावित करती है। राजनीतिक दल चुनावी रणनीति तैयार करते समय निर्वाचन क्षेत्रों के जातिगत आंकड़ों का सूक्ष्म विश्लेषण करते हैं। वे प्रायः उन उम्मीदवारों को प्राथमिकता देते हैं जिनकी जाति का उस क्षेत्र में बाहुल्य होता है। यह प्रथा मतदाताओं को गोलबंद करने का

Click Here to Buy book on Amazon

नहीं किया जा सकता। ये प्रावधान राज्य की मनमानी शक्ति पर अंकुश लगाते हैं और व्यक्तिगत न्याय सुनिश्चित करते हैं।

104. (A) किसी कर का अधिरोपण, उत्सादन या विनियमन
अनुच्छेद 110 के अनुसार, किसी विधेयक को 'धन विधेयक' तब माना जाता है जब उसमें कर लगाने, ऋण लेने या संचित निधि से धन निकालने जैसे वित्तीय मामले शामिल हों। धन विधेयक की पहचान करने का अंतिम अधिकार लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है। यह विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है और इस पर राज्यसभा की शक्तियां सीमित होती हैं। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि वित्त के मामलों में जनता के निर्वाचित सदन का ही वर्चस्व रहे।

105. (A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
भारत की संसदीय प्रणाली में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। राष्ट्रपति देश के संवैधानिक प्रमुख होते हैं और भारतीय गणराज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। वहीं, प्रधानमंत्री सरकार के वास्तविक प्रमुख होते हैं और मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करते हुए शासन का संचालन करते हैं। सभी सरकारी निर्णय राष्ट्रपति के नाम पर लिए जाते हैं, परंतु व्यावहारिक रूप से इन शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री की सलाह पर ही किया जाता है, जो लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व का आधार है।

106. (A) अनुच्छेद 263
अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति को राज्यों और केंद्र के बीच समन्वय हेतु अंतर-राज्य परिषद स्थापित करने की शक्ति प्राप्त है। यह परिषद राज्यों के बीच विवादों की जांच और साझा हितों पर चर्चा हेतु मंच प्रदान करती है। यह सहकारी संघवाद के विचार को सुदृढ़ करती है और सुचारु प्रशासन हेतु आवश्यक सहयोग का माहौल तैयार करती है। सरकारिया आयोग की सिफारिश पर 1990 में पहली बार इस परिषद का विधिवत गठन किया गया था।

107. (D) हुसनआरा खातून बनाम गृह सचिव, बिहार
हुसैनआरा खातून मामला (1979) जनहित याचिका के इतिहास में महत्वपूर्ण मोड़ था। सर्वोच्च न्यायालय ने जेलों में बंद हजारों विचाराधीन कैदियों की दुर्दशा पर ध्यान दिया। इस मामले ने 'त्वरित न्याय के अधिकार' को अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित किया। इसने न्यायपालिका को उन लोगों की सहायता हेतु आगे बढ़ने की अनुमति दी जो स्वयं अपनी रक्षा में अक्षम थे, जिससे न्यायिक सक्रियता का नया युग प्रारंभ हुआ।

108. (B) विरोध प्रदर्शनों का अचानक और असंगठित रूप से फूटना।
एनोमिक दबाव समूह वे होते हैं जिनका कोई स्थायी संगठन या औपचारिक संरचना नहीं होती। ये समूह अचानक सामाजिक तनाव या असंतोष के विरोध में स्वतः स्फूर्त रूप से उभरते हैं। इनके प्रदर्शनों में दंगों या अचानक होने वाली रैलियों जैसी गतिविधियां शामिल हो सकती हैं। चूँकि इनका कोई स्पष्ट नेतृत्व नहीं होता, इसलिए ये अस्थायी प्रकृति के होते हैं। हालांकि अपनी तीव्रता के कारण ये अल्पकालिक रूप से सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं।

109. (C) 61वां संशोधन अधिनियम
1988 के 61वें संशोधन अधिनियम ने भारत में लोकतंत्र के आधार को व्यापक बनाया। इसके माध्यम से मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। यह निर्णय युवा पीढ़ी की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने और उन्हें राष्ट्र-निर्माण में शामिल करने के उद्देश्य से लिया गया था। इसने करोड़ों नए मतदाताओं को चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा बनाया, जिससे चुनाव अधिक समावेशी हुए और युवाओं की आकांक्षाओं को उचित और प्रभावी प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सका।

NODIA

110. (A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
क्षेत्रवाद राष्ट्र-निर्माण हेतु एक गंभीर चुनौती है क्योंकि यह संकीर्ण क्षेत्रीय हितों को राष्ट्रीय हितों से ऊपर रखता है। जब किसी क्षेत्र के लोग अपनी भाषाई पहचान के आधार पर अत्यधिक लगाव महसूस करते हैं, तो वे केंद्र की उपेक्षा के विरुद्ध मुखर हो जाते हैं। यह भावना कभी-कभी अलगाववादी मांगों या हिंसक आंदोलनों में बदल सकती है, जो राष्ट्रीय एकता को कमजोर करती है। अतः अभिकथन और कारण दोनों एक दूसरे से तर्कसंगत और विधिक रूप से जुड़े हुए हैं।

111. (A) विशेष रूप से गठित आयोग द्वारा संविधान के कामकाज की समय-समय पर समीक्षा करने की प्रक्रिया।
संवैधानिक समीक्षा का तात्पर्य संविधान के लागू होने के बाद उसके प्रावधानों की प्रभावशीलता का आकलन करने से है। वर्ष 2000 में 'संविधान के कामकाज की समीक्षा हेतु राष्ट्रीय आयोग' का गठन किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य यह देखना था कि क्या मौजूदा ढांचे ने समय के साथ बदलती राष्ट्रीय जरूरतों को सफलतापूर्वक पूरा किया है। यह समीक्षा संशोधन का विकल्प नहीं है, बल्कि सुधार हेतु सुझाव देने वाला एक उच्च-स्तरीय और विशेषज्ञों का मूल्यांकन अभ्यास है।

112. (B) एक लिखित संविधान और न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है।
भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश मॉडल पर आधारित होने के बावजूद कुछ अर्थों में भिन्न है। ब्रिटेन में संसद संप्रभु है और वहां कोई लिखित संविधान नहीं है, जबकि भारत में संविधान सर्वोच्च है। भारत में न्यायपालिका को कानूनों की समीक्षा करने और उन्हें असंवैधानिक घोषित करने की शक्ति प्राप्त है। इसके अतिरिक्त, भारत एक गणराज्य है जहाँ राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, जबकि ब्रिटेन में राष्ट्र का प्रमुख एक वंशानुगत सम्राट या राजतंत्रात्मक प्रमुख होता है।

113. (B) दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से।
यदि किसी साधारण विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध उत्पन्न होता है, तो अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। इस बैठक में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से निर्णय लिया जाता है। चूँकि लोकसभा की सदस्य संख्या अधिक है, इसलिए प्रायः संयुक्त बैठक में निचले सदन का ही वर्चस्व रहता है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि विधायी कार्य रुके नहीं और महत्वपूर्ण कानूनों को पारित किया जा सके।

114. (A) दलित पैंथर्स
'दलित' शब्द को 1970 के दशक में महाराष्ट्र के 'दलित पैंथर्स' आंदोलन द्वारा एक राजनीतिक पहचान के रूप में लोकप्रिय बनाया गया था। इससे पूर्व इस वर्ग हेतु 'अनुसूचित जाति' जैसे शब्दों का प्रयोग अधिक था। दलित पैंथर्स ने इस शब्द का उपयोग उत्पीड़ित वर्गों के प्रतिरोध और अपनी पहचान के प्रति गर्व को व्यक्त करने हेतु किया। इस आंदोलन ने दलित राजनीति में नई ऊर्जा का संचार किया, जिसने बाद में सामाजिक न्याय के संघर्षों को प्रभावित किया।

115. (C) 552
भारतीय संविधान के अनुसार, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 निर्धारित की गई है। इनमें से 530 सदस्य राज्यों और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। एंग्लो-इंडियन समुदाय हेतु मनोनीत करने का प्रावधान अब समाप्त कर दिया गया है। वर्तमान में प्रभावी सदस्य संख्या 543 है। सीटों का आवंटन जनसंख्या के आधार पर किया जाता है, जिससे सभी क्षेत्रों को संसद में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सके और विधायी प्रक्रिया में सभी की भागीदारी सुनिश्चित हो।

116. (C) P-3, Q-4, R-1, S-2
अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 40 राज्य को ग्राम पंचायतों को संगठित करने और उन्हें स्वशासन की शक्ति देने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को क्षमादान देने की शक्ति प्रदान करता है, जो एक महत्वपूर्ण न्यायिक-कार्यकारी शक्ति है। वहीं, अनुच्छेद 368 संसद को संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया और शक्ति प्रदान करता है, जो संविधान को समय के साथ बदलने और राष्ट्रहित में प्रासंगिक बनाए रखने हेतु आवश्यक है।

117. (C) चौथी अनुसूची
भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है। प्रत्येक राज्य को दी जाने वाली सीटों की संख्या उसकी जनसंख्या के आधार पर निर्धारित की जाती है। यह व्यवस्था संघीय संतुलन हेतु महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सुनिश्चित करती है कि ऊपरी सदन में प्रत्येक राज्य का प्रतिनिधित्व उसकी आबादी के अनुपात में हो। राज्यसभा सदस्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, जो केंद्र में राज्यों की आवाज़ बनते हैं।

118. (B) नियमित रूप से करों का भुगतान करना।
अनुच्छेद 51A के तहत सूचीबद्ध 11 मौलिक कर्तव्यों में नियमित करों का भुगतान शामिल नहीं है। यद्यपि कर देना एक महत्वपूर्ण नागरिक जिम्मेदारी है, परंतु इसे 'मौलिक कर्तव्य' के रूप में नहीं रखा गया है। संविधान का पालन, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण प्रमुख मौलिक कर्तव्य हैं। इन कर्तव्यों का उद्देश्य नागरिकों में नैतिकता और उत्तरदायित्व की भावना पैदा करना है, जिससे वे राष्ट्र के विकास और एकता में सक्रिय योगदान दे सकें।

119. (D) पैरवी के लिए औपचारिक संगठन और संरचना।
दबाव समूह और सामाजिक आंदोलन दोनों सार्वजनिक नीति को प्रभावित करना चाहते हैं, परंतु उनकी संरचना में अंतर होता है। दबाव समूह प्रायः सुसंगठित होते हैं और उनकी औपचारिक संरचना होती है, जो निरंतर अधिकारियों और विधायकों के साथ पैरवी करते हैं। इसके विपरीत, सामाजिक आंदोलन अक्सर अधिक अनौपचारिक और स्वतः स्फूर्त होते हैं, जिनका आधार व्यापक जनता और विशेष सामाजिक परिवर्तन की मांग होती है। दबाव समूह विशिष्ट हितों हेतु अधिक संगठित तरीके अपनाते हैं।

120. (D) I, II और III
निर्वाचन आयोग एक बहु-सदस्यीय निकाय है जिसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो अन्य आयुक्त होते हैं। इसकी निष्पक्षता हेतु मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही कठिन है। आयोग का मुख्य कार्य प्रत्येक चुनाव से पूर्व शुद्ध और अद्यतन मतदाता सूची तैयार करना सुनिश्चित करना है। ये सभी विशेषताएं निर्वाचन आयोग को विश्व के सबसे शक्तिशाली और स्वतंत्र चुनाव निकायों में से एक बनाती हैं, जो लोकतंत्र की रक्षा करती हैं।

121. (C) केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य
1973 का केशवानंद भारती मामला भारतीय संवैधानिक इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय माना जाता है। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने 'मूल संरचना' का सिद्धांत प्रतिपादित किया। न्यायालय ने व्यवस्था दी कि संसद के पास संशोधन की व्यापक शक्ति है, परंतु वह संविधान के उन बुनियादी तत्वों को नहीं बदल सकती जो इसकी नींव हैं। इस सिद्धांत ने संविधान की सर्वोच्चता को पुनः स्थापित किया और न्यायपालिका को संसद की मनमानी शक्तियों पर अंकुश लगाने का सशक्त उपकरण प्रदान किया।

122. (A) किसी भी एक दल या चुनाव पूर्व गठबंधन को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है।
'त्रिशंकु संसद' उस स्थिति को कहते हैं जब चुनाव के बाद किसी एक दल या गठबंधन के पास सरकार बनाने हेतु आवश्यक बहुमत नहीं होता। ऐसी स्थिति में सरकार बनाने हेतु अक्सर छोटे दलों के समर्थन की आवश्यकता पड़ती है, जिससे गठबंधन की राजनीति और सौदेबाजी शुरू होती है। इसमें सरकारों में अस्थिरता की संभावना रहती है और नीति निर्माण की प्रक्रिया जटिल हो जाती है, क्योंकि सरकार को विभिन्न परस्पर विरोधी हितों के बीच संतुलन बनाना पड़ता है।

123. (D) अन्य मंत्रियों की नियुक्ति पर राष्ट्रपति को सलाह देना।
प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के वास्तविक नेता होते हैं। उनकी सबसे प्रमुख शक्तियों में राष्ट्रपति को मंत्रियों की नियुक्ति और उनके विभागों के आवंटन के संबंध में सलाह देना शामिल है। राष्ट्रपति केवल उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त करते हैं जिनकी सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री मंत्रियों के बीच कार्य का वितरण करते हैं और यदि आवश्यक हो, तो

Downloaded from www.pdf.tube

किसी मंत्री से त्यागपत्र मांग सकते हैं। यह पद शासन प्रणाली में केंद्रीय और अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

124. (B) संयुक्त राज्य अमेरिका
जनहित याचिका (पी.आई.एल.) की अवधारणा का उद्भव संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था, जहाँ इसे सार्वजनिक हितों की रक्षा हेतु शुरू किया गया था। भारत में इस अवधारणा को 1970 के दशक के उत्तरार्ध में न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती और न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्ण अय्यर द्वारा विकसित किया गया। इसने भारतीय कानूनी व्यवस्था में 'वाद के अधिकार' के नियम को उदार बनाकर सामान्य नागरिकों हेतु न्याय के द्वार खोल दिए, जिससे हाशिए पर रहने वाले लोगों को सशक्तिकरण प्राप्त हुआ।

125. (C) न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व
भारतीय संविधान की प्रस्तावना उन सर्वोच्च आदर्शों को स्पष्ट करती है जिन्हें राष्ट्र प्राप्त करना चाहता है। यह सभी नागरिकों हेतु सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने की घोषणा करती है। इसके साथ ही अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की स्वतंत्रता का वादा किया गया है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्रदान करना इसका मुख्य लक्ष्य है। इन सबके बीच बंधुत्व की भावना को बढ़ावा देने पर बल दिया गया है ताकि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित हो सके।

126. (C) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
नीति निदेशक तत्व (डी.पी.एस.पी.) शासन में मौलिक महत्व रखते हैं और नीतियों के निर्माण हेतु मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में कार्य करते हैं। हालांकि, ये मौलिक अधिकारों के विपरीत न्यायालयों द्वारा सीधे प्रवर्तनीय नहीं हैं। इसका अर्थ है कि यदि राज्य इनका पालन नहीं करता, तो नागरिक न्यायालय में इनके क्रियान्वयन की मांग नहीं कर सकते। इन्हें केवल विधायी प्रक्रियाओं के माध्यम से ही लागू किया जा सकता है। सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि वह इन्हें शासन में व्यावहारिक रूप दे।

127. (A) अनुच्छेद 32
डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को 'संविधान का हृदय और आत्मा' कहा था। उनका मानना था कि अधिकारों की सूची व्यर्थ है जब तक उन्हें लागू करने का प्रभावी तंत्र न हो। यह अनुच्छेद नागरिकों को अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है। न्यायालय रिट जारी कर इन अधिकारों की रक्षा करता है। यह प्रावधान संविधान के रक्षक के रूप में कार्य करता है, जिससे लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक के न्याय की सुरक्षा सुनिश्चित होती है।

128. (D) संसद के किसी भी सदन में।
राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है। इसके लिए संविधान के उल्लंघन का आरोप होना आवश्यक है। जिस सदन में आरोप लगाया जाता है, उसके एक-चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ 14 दिन का नोटिस देना अनिवार्य है। यदि वह सदन दो-तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देता है, तो दूसरा सदन आरोपों की जांच करता है। दोनों सदनों द्वारा पारित होने पर राष्ट्रपति को पद छोड़ना पड़ता है। यह एक अत्यंत गंभीर प्रक्रिया है।

NODIA

129. (B) राज्य विधायिका की विधायी क्षमता।
'क्षेत्रीय संबंध का सिद्धांत' यह निर्धारित करता है कि क्या किसी राज्य द्वारा बनाया गया कानून उसकी सीमाओं के बाहर भी प्रभावी हो सकता है। सामान्यतः राज्य विधायिका केवल अपने क्षेत्र हेतु कानून बनाती है। हालांकि, यदि उस कानून और राज्य के बीच एक स्पष्ट और वास्तविक संबंध स्थापित हो जाए, तो वह कानून राज्य की सीमाओं के बाहर भी लागू हो सकता है। यह सिद्धांत विधायी शक्तियों के भौगोलिक दायरे को स्पष्ट करने और केंद्र-राज्य विवादों को सुलझाने में न्यायपालिका की सहायता करता है।

130. (A) नौकरशाही
संस्थागत दबाव समूह वे होते हैं जो शासन के औपचारिक ढांचे का हिस्सा होते हैं और अपनी स्थिति के कारण सरकारी निर्णयों को प्रभावित करते हैं। नौकरशाही इसका प्रमुख उदाहरण है क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी नीतियों के निर्माण और कार्यान्वयन में सीधे शामिल होते हैं। वे अपने हितों और दृष्टिकोण को प्रभावी ढंग से नीति प्रक्रिया में सम्मिलित करने की क्षमता रखते हैं। अन्य उदाहरणों में सेना और विधायी समितियां शामिल हो सकती हैं। ये समूह सत्ता के केंद्रों के अत्यंत निकट होते हैं।

131. (C) जैसे ही निर्वाचन आयोग चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करता है।
आदर्श आचार संहिता दिशा-निर्देशों का समूह है जिसे निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने हेतु लागू किया जाता है। यह निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की तिथि से ही प्रभावी हो जाती है। यह संहिता राजनीतिक दलों के आचरण, प्रचार के तरीकों और सरकार द्वारा नई योजनाओं की घोषणा पर प्रतिबंध लगाती है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सत्तारूढ़ दल को अपनी स्थिति का अनुचित लाभ न मिले और सभी उम्मीदवारों को चुनाव हेतु एक समान अवसर प्राप्त हो।

132. (D) अपनी जाति के प्रति अत्यधिक वफादारी जो संघर्ष का कारण बनती है और राष्ट्रीय हित को क्षति पहुँचाती है।
राष्ट्र-निर्माण के संदर्भ में जातिवाद एक संकीर्ण भावना है जहाँ व्यक्ति राष्ट्रीय पहचान की तुलना में अपनी जाति को अधिक प्राथमिकता देता है। यह स्थिति समाज में ध्रुवीकरण पैदा करती है और समूहों के बीच प्रतिस्पर्धा का कारण बनती है। राजनीति में इसका उपयोग अक्सर वोट बैंक बनाने हेतु किया जाता है, जिससे योग्यता की उपेक्षा होती है। जातिवाद सामाजिक न्याय के मार्ग में बाधा डालता है और एक एकीकृत राष्ट्रीय पहचान के विकास को धीमा करता है, जो लोकतांत्रिक स्थिरता को कमजोर करता है।

133. (A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के संरक्षक के रूप में स्थापित करती है। चूँकि संविधान सर्वोच्च कानून है, इसलिए संसद द्वारा किया गया

188. (C) नीति आयोग
नीति आयोग एक 'कार्यकारी निकाय' है, न कि संवैधानिक या वैधानिक। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा की गई थी। इसके विपरीत, निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग और वित्त आयोग का उल्लेख सीधे संविधान के विशिष्ट अनुच्छेदों में किया गया है, जो उन्हें संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। नीति आयोग का मुख्य कार्य सरकार के 'थिंक टैंक' के रूप में कार्य करना और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना है। यह बॉटम-अप दृष्टिकोण के माध्यम से नीति निर्माण में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करता है।

189. (C) उन दृष्टिकोणों, विश्वासों और भावनाओं का समूह जो राजनीतिक प्रक्रिया को व्यवस्था और अर्थ प्रदान करते हैं।
'राजनीतिक संस्कृति' उस मनोवैज्ञानिक आधार को संदर्भित करती है जिस पर एक समाज की राजनीतिक व्यवस्था टिकी होती है। इसमें नागरिकों का व्यवस्था के प्रति विश्वास, उनके लोकतांत्रिक मूल्य और राजनीति में भागीदारी का स्तर शामिल होता है। यह संस्कृति पीढ़ी-दर-पीढ़ी हस्तांतरित होती है और यह निर्धारित करती है कि लोग सत्ता और अपने अधिकारों को किस दृष्टि से देखते हैं। एक सुदृढ़ राजनीतिक संस्कृति लोकतंत्र की स्थिरता और चुनावों में मतदाताओं की सचेत भागीदारी हेतु अत्यंत आवश्यक है, जो शासन को व्यापक जन-आधार प्रदान करती है।

190. (D) भाषाई आधार पर नए राज्यों का निर्माण।
राजनीति में लिंग आधारित मुद्दों का संबंध महिलाओं के अधिकारों और उनकी सुरक्षा से है। इसमें विधायी निकायों में 33 प्रतिशत आरक्षण की मांग और कन्या भ्रूण हत्या जैसी कुरीतियों के विरुद्ध कानून बनाना शामिल है। भाषाई आधार पर नए राज्यों का निर्माण एक क्षेत्रीय और प्रशासनिक मुद्दा है, जिसका महिलाओं की विशिष्ट समस्याओं से प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। लिंग आधारित राजनीति का मुख्य उद्देश्य पितृसत्तात्मक ढांचे को चुनौती देना और महिलाओं हेतु समान सामाजिक-राजनीतिक स्थान सुनिश्चित करना है, जो सामाजिक न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण है।

191. (D) संप्रभु, लोकतांत्रिक, गणराज्य
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत वे लोकतांत्रिक मूल्य थे जो औपनिवेशिक संघर्ष के दौरान विकसित हुए। संविधान निर्माताओं ने ऐसे भारत की कल्पना की जो पूर्णतः संप्रभु हो और जहाँ सत्ता जनता के हाथ में हो। 'गणराज्य' होने का अर्थ था कि देश का प्रमुख निर्वाचित होगा। ये मूल्य केवल राजनीतिक ढांचे तक सीमित नहीं थे, बल्कि इनका उद्देश्य एक न्यायपूर्ण और समतावादी समाज का निर्माण करना था। यह विदेशी अधीनता से मुक्ति के बाद राष्ट्र की वास्तविक आकांक्षाओं का प्रतीक बना, जिसने भारतीय लोकतंत्र को एक सुदृढ़ नैतिक आधार प्रदान किया।

192. (D) यह विभिन्न स्रोतों से अपनाई गई विशेषताओं का मिश्रण है।
भारतीय संविधान की एक अद्वितीय विशेषता इसकी व्यापकता और विभिन्न वैश्विक परंपराओं का समावेश है। निर्माताओं ने विश्व के प्रमुख संविधानों के सर्वोत्तम प्रावधानों को भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल अपनाकर एक जीवंत दस्तावेज तैयार किया। उदाहरण हेतु, संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से और मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। यह मिश्रण इसे एक लचीला और समावेशी संविधान बनाता है जो देश की विविधता और शासन की जटिल जरूरतों को सफलतापूर्वक संबोधित करने में सक्षम है। यह भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप एक मौलिक और दूरदर्शी विधिक ढांचा है।

193. (B) समानता का अधिकार
अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 के तहत 'समानता के अधिकार' का एक अभिन्न अंग है। यह प्रावधान सदियों से चली आ रही भेदभावपूर्ण प्रथा को समाप्त करने हेतु किया गया है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के किसी भी रूप में आचरण को प्रतिबंधित करता है और इसे कानून के अनुसार एक दंडनीय अपराध बनाता है। यह सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन का एक सशक्त संवैधानिक साधन है जिसका उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान और समानता के साथ जीने का अवसर प्रदान करना है। यह प्रावधान दलित और वंचित वर्गों के सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में निर्णायक कदम है।

194. (C) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।
संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन में किसी भी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है; इसके लिए राष्ट्रपति द्वारा प्रारंभ किया जाना अनिवार्य नहीं है। हालांकि, अधिकांश संशोधनों हेतु संसद के दोनों सदनों में 'विशेष बहुमत' की आवश्यकता होती है, जिसका अर्थ है कुल सदस्यता का बहुमत और उपस्थित सदस्यों का दो-तिहाई हिस्सा। कुछ संघीय मामलों में राज्यों के अनुसमर्थन की भी आवश्यकता होती है। यह प्रक्रिया संविधान की पवित्रता बनाए रखती है और सुनिश्चित करती है कि महत्वपूर्ण परिवर्तन केवल व्यापक विधायी सहमति से ही संभव हो सकें।

195. (C) संपूर्ण मंत्रिपरिषद का विघटन।
प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के नेता और मुख्य आधार होते हैं। उनकी नियुक्ति के आधार पर ही अन्य मंत्रियों का पद टिका होता है, इसलिए उनके त्यागपत्र या मृत्यु की स्थिति में पूरी मंत्रिपरिषद स्वतः ही भंग हो जाती है। यह संसदीय प्रणाली के सामूहिक उत्तरदायित्व और प्रधानमंत्री के केंद्रीय वर्चस्व के सिद्धांत का परिणाम है। यद्यपि राष्ट्रपति नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकते हैं, परंतु पुरानी मंत्रिपरिषद का अस्तित्व प्रधानमंत्री के हटने के साथ ही समाप्त हो जाता है। यह व्यवस्था सरकार के नेतृत्व में आने वाले रिक्त स्थान को संबोधित करती है।

196. (D) समवर्ती सूची
सातवीं अनुसूची के तहत 'समवर्ती सूची' में वे विषय शामिल हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। इनमें शिक्षा, वन और विवाह जैसे विषय शामिल हैं जो दोनों सरकारों

Click Here to Buy book on Amazon

बहुमत के समर्थन पर टिकी होती है। यह व्यवस्था जवाबदेह शासन हेतु आवश्यक है, जिससे जनता की इच्छाओं को शासन में सर्वोच्च प्राथमिकता प्राप्त होती है।

143. (B) केवल I और II
लोकतंत्र में मीडिया को 'चतुर्थ स्तंभ' माना जाता है क्योंकि यह सूचनाओं के निष्पक्ष प्रसार और शासन की गतिविधियों पर निगरानी रखने का कार्य करता है। यह जनमत तैयार करने और जटिल मुद्दों पर जनता को शिक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि यह कहना गलत होगा कि मीडिया पूर्णतः मुक्त है; इसे मानहानि कानूनों और कुछ उचित कानूनी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है। फिर भी, एक स्वतंत्र और जिम्मेदार मीडिया स्वस्थ लोकतंत्र की बुनियादी आवश्यकता है जो पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देती है।

144. (B) राष्ट्रपति का चुनाव और उसकी प्रक्रिया
संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों में संशोधन हेतु विशेष बहुमत के साथ-साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों की सहमति अनिवार्य है। राष्ट्रपति का चुनाव और उसकी प्रक्रिया इसी श्रेणी में आती है क्योंकि यह सीधे देश के संघीय ढांचे को प्रभावित करती है। अन्य उदाहरणों में सातवीं अनुसूची और संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व शामिल है। यह व्यवस्था केंद्र को राज्यों के अधिकारों या संघीय संतुलन के साथ मनमाना परिवर्तन करने से रोकती है, जिससे भारतीय संघवाद की स्थिरता और अखंडता सुनिश्चित होती है।

145. (B) समानों में प्रथम।
'समानों में प्रथम' संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री को वर्णित करने वाला प्रमुख वाक्यांश है। वे कैबिनेट के अन्य मंत्रियों के समान ही सदस्य होते हैं, परंतु उनका पद उन्हें नेतृत्व प्रदान करता है। वे मंत्रिपरिषद के प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं और विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित करते हैं। यद्यपि वे सामूहिक उत्तरदायित्व साझा करते हैं, परंतु उनकी निर्णय लेने की शक्ति और राजनीतिक स्थिति उन्हें कैबिनेट में सबसे प्रभावशाली और केंद्रीय स्थान प्रदान करती है, जो शासन के सुचारू संचालन हेतु आवश्यक है।

146. (A) अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण
1992 का इंदिरा साहनी मामला, जिसे 'मंडल मामला' भी कहा जाता है, आरक्षण नीति के संदर्भ में ऐतिहासिक निर्णय था। न्यायालय ने अन्य पिछड़े वर्गों (ओ.बी.सी.) हेतु 27 प्रतिशत आरक्षण की संवैधानिकता को बरकरार रखा, परंतु 'क्रीमी लेयर' का सिद्धांत प्रस्तुत किया। न्यायालय ने व्यवस्था दी कि कुल आरक्षण 50 प्रतिशत की सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए। इस निर्णय ने भारत में आरक्षण और सामाजिक न्याय के ढांचे को कानूनी स्पष्टता प्रदान की, जिससे वंचित वर्गों के लाभ का उचित वितरण सुनिश्चित हुआ।

147. (C) भू-राजस्व में वृद्धि।
बारदोली सत्याग्रह 1928 में गुजरात में हुआ एक प्रमुख किसान आंदोलन था, जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभभाई पटेल ने किया था। यह आंदोलन ब्रिटिश सरकार द्वारा भू-राजस्व में अचानक 22 प्रतिशत की भारी वृद्धि करने के विरुद्ध था। किसानों ने लगान देने से इनकार कर दिया और अहिंसक प्रतिरोध का मार्ग अपनाया। इस आंदोलन की सफलता ने पटेल को महान राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित किया। अंततः सरकार को झुकना पड़ा और राजस्व वृद्धि वापस लेनी पड़ी। यह किसानों की संगठित शक्ति का प्रतीक बना।

148. (D) भारत का निर्वाचन आयोग
भारत का निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों को उनके प्रदर्शन के आधार पर राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दलों के रूप में मान्यता प्रदान करने हेतु अधिकृत निकाय है। इसके लिए आयोग ने विशिष्ट मानदंड निर्धारित किए हैं, जैसे पिछले चुनावों में प्राप्त मतों का प्रतिशत और सीटों की संख्या। मान्यता प्राप्त दलों को विशेष चुनावी प्रतीक आवंटित किए जाते हैं और उन्हें प्रचार हेतु कुछ विशेष लाभ प्राप्त होते हैं। यह प्रक्रिया देश में एक सुव्यवस्थित और बहु-दलीय राजनीतिक व्यवस्था को संचालित करने के लिए आवश्यक है।

149. (B) शक्तियों का पृथक्करण
न्यायिक सक्रियता को अक्सर 'शक्तियों के पृथक्करण' के सिद्धांत के साथ संघर्ष में देखा जाता है क्योंकि यह सिद्धांत शासन के अंगों के कार्यों को अलग रखने पर बल देता है। जब न्यायपालिका कार्यपालिका को निर्देश देती है या नीति निर्माण से संबंधित आदेश जारी करती है, तो इसे कार्यकारी क्षेत्र में अतिक्रमण माना जा सकता है। आलोचकों का तर्क है कि न्यायपालिका को केवल कानूनों की व्याख्या करनी चाहिए। हालांकि, समर्थकों के अनुसार, यह तब आवश्यक है जब अन्य अंग अपने संवैधानिक कर्तव्यों को निभाने में विफल रहते हैं।

150. (B) P-3, Q-4, R-2, S-1
नीति निदेशक तत्व विभिन्न वैचारिक धाराओं का समावेश हैं। समाजवादी सिद्धांतों के तहत संसाधनों के न्यायसंगत वितरण का लक्ष्य रखा गया है। गांधीवादी सिद्धांतों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था हेतु कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना शामिल है। उदारवादी सिद्धांतों के अंतर्गत सभी नागरिकों हेतु समान नागरिक संहिता (अनुच्छेद 44) की वकालत की गई है। अंतरराष्ट्रीय सिद्धांतों के तहत अनुच्छेद 51 राज्य को अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का निर्देश देता है, जो वैश्विक सद्भाव और न्यायपूर्ण राष्ट्र संबंधों हेतु आवश्यक है।

151. (D) भारत सरकार अधिनियम, 1935
भारत सरकार अधिनियम 1935 संवैधानिक इतिहास का अत्यंत विस्तृत और महत्वपूर्ण दस्तावेज था। इसने पहली बार प्रांतों में 'प्रांतीय स्वायत्तता' की शुरुआत की, जिससे उन्हें आंतरिक प्रशासन में ब्रिटिश नियंत्रण से काफी स्वतंत्रता मिली। इस अधिनियम ने केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया और संघीय ढांचे की रूपरेखा प्रस्तुत की। यद्यपि पूर्ण स्वराज्य अभी दूर था, परंतु इस अधिनियम के कई प्रावधानों को बाद में स्वतंत्र भारत के संविधान में बुनियादी ढांचे के रूप में अपनाया गया था।

Downloaded from www.pdf.tube

कोई भी कार्य जो संविधान के विरुद्ध हो, वह अवैध माना जाता है। न्यायालय के पास यह अधिकार है कि वह ऐसे किसी भी कानून की समीक्षा करे और उसे असंवैधानिक घोषित कर दे। यह व्यवस्था शक्तियों के संतुलन को बनाए रखती है और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है। अतः कारण अभिकथन के लिए तार्किक आधार प्रदान करता है।

134. (B) दोहरी सदस्यता
भारतीय संसदीय प्रणाली में दोहरी सदस्यता का अर्थ है कि मंत्री अनिवार्य रूप से विधायिका के सदस्य होते हैं। विकल्प (B) में 'दोहरी सदस्यता' को विशेषता न बताना संभवतः अन्य प्रणालियों के संदर्भ में भ्रम हो सकता है। भारतीय प्रणाली में शक्तियों का कठोर पृथक्करण नहीं बल्कि समन्वय होता है। बहुमत दल का शासन और मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व इस प्रणाली की वास्तविक विशेषताएं हैं जो उत्तरदायी शासन सुनिश्चित करती हैं। यह व्यवस्था सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह बनाए रखती है।

135. (B) एक-तिहाई
73वें संशोधन अधिनियम ने स्थानीय स्वशासन में महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु क्रांतिकारी कदम उठाया। इस कानून के तहत पंचायतों के सभी स्तरों पर कुल सीटों का कम से कम एक-तिहाई भाग महिलाओं के लिए आरक्षित करना अनिवार्य कर दिया गया। यह आरक्षण विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में लागू होता है। कई राज्यों ने अब इस सीमा को बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया है। इस प्रावधान ने ग्रामीण भारत में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी और उनके नेतृत्व क्षमता को विकसित करने में अभूतपूर्व भूमिका निभाई है।

136. (A) पश्चिम बंगाल
'गोरखालैंड' की मांग पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग, विशेषकर दार्जिलिंग क्षेत्र में रहने वाले नेपाली भाषी गोरखा समुदाय द्वारा की जाती रही है। यह मांग भाषाई विशिष्टता और आर्थिक विकास की उपेक्षा के आधार पर एक अलग राज्य बनाने हेतु है। इस मुद्दे ने समय-समय पर राजनीतिक अस्थिरता को जन्म दिया है। हालांकि स्वायत्त परिषदों के माध्यम से कुछ शक्तियां दी गई हैं, परंतु पृथक राज्य की मांग अभी भी एक संवेदनशील क्षेत्रीय मुद्दा है। यह भारत की आंतरिक विविधता और शासन के बीच संतुलन का प्रश्न है।

137. (C) इंद्रजीत गुप्त समिति
1998 में गठित इंद्रजीत गुप्त समिति ने चुनावों के 'राज्य वित्तपोषण' के विचार का समर्थन किया था। समिति का तर्क था कि इससे चुनावों में काले धन के प्रभाव को कम किया जा सकता है और ईमानदार उम्मीदवारों को समान अवसर मिल सकता है। इसने सुझाव दिया कि यह वित्तपोषण नकद के स्थान पर सुविधाओं के रूप में दिया जाना चाहिए। चुनावी सुधारों की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव था, जिसका उद्देश्य राजनीति के बढ़ते व्यावसायीकरण को रोकना और लोकतंत्र की पवित्रता एवं शुचिता बनाए रखना था।

138. (A) लोकतंत्र और समानता जैसे मूल्यों को बढ़ावा देकर जो मार्गदर्शक सिद्धांत बने
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन केवल स्वतंत्रता प्राप्ति का संघर्ष नहीं था, बल्कि यह नए भारत के मूल्यों को गढ़ने की प्रक्रिया भी थी। आंदोलन के दौरान लोकतंत्र, नागरिक स्वतंत्रता और समानता के प्रति जो प्रतिबद्धता विकसित हुई, वही संविधान की नींव बनी। नेताओं के विचारों ने सामाजिक न्याय को संवैधानिक ढांचे में समाहित करने हेतु प्रेरित किया। राष्ट्रीय आंदोलन ने जनता में राजनीतिक चेतना जागृत की, जिससे संविधान को एक लोकप्रिय जनादेश और नैतिक वैधता प्राप्त हुई, जो इसकी दीर्घकालिक सफलता का मुख्य कारण है।

NODIA

139. (D) बंदी प्रत्यक्षीकरण
'बंदी प्रत्यक्षीकरण' की रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण विधिक साधन है। यह रिट न केवल सरकारी अधिकारियों, बल्कि किसी निजी व्यक्ति के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है यदि उसने किसी को अवैध रूप से कैद किया हो। न्यायालय इसके माध्यम से बंदी को अपने समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश देता है और यदि हिरासत का कानूनी आधार नहीं पाया जाता, तो उसे तुरंत रिहा करने का आदेश दिया जाता है। यह प्रावधान नागरिक की मनमानी गिरफ्तारी के विरुद्ध सर्वोच्च संवैधानिक सुरक्षा है।

140. (B) 1, 4, 2, 3
संविधान के विभिन्न भागों का क्रम राष्ट्र निर्माण की क्रमिक प्रक्रिया को दर्शाता है। संविधान भाग 1 के साथ शुरू होता है, जो संघ और उसके राज्य क्षेत्रों को परिभाषित करता है। इसके तुरंत बाद भाग 2 में नागरिकता के प्रावधान दिए गए हैं। फिर भाग 3 में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का विस्तृत विवरण है। अंत में, भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्वों को शामिल किया गया है। यह क्रम देश की भौगोलिक स्थिति, उसकी जनता और उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों की प्राथमिकता को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है।

141. (C) सर्वोच्च न्यायालय
सर्वोच्च न्यायालय संविधान के अंतिम व्याख्याकार और संरक्षक के रूप में कार्य करता है। इसके पास यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है कि सरकार का कोई भी अंग संविधान की सीमाओं का उल्लंघन न करे। यदि संसद ऐसा कानून बनाती है जो मूल ढांचे के विरुद्ध हो, तो सर्वोच्च न्यायालय उसे अमान्य घोषित कर सकता है। न्यायालय के निर्णय सभी अधीनस्थ अदालतों और अधिकारियों हेतु बाध्यकारी होते हैं। यह संस्थागत भूमिका संविधान की सर्वोच्चता और कानून के शासन की निरंतरता को प्रभावी ढंग से सुरक्षित रखती है।

142. (D) विधानसभा
राज्य सरकार में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि कार्यपालिका पर सीधे निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का नियंत्रण रहे। यदि विधानसभा सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देती है, तो मुख्यमंत्री सहित पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। इस प्रकार, सरकार की वैधता विधानसभा के

161. (B) राष्ट्रीय एकता की कीमत पर एक विशिष्ट क्षेत्र के प्रति वफादारी।
क्षेत्रवाद एक ऐसी प्रवृत्ति है जहाँ लोग अपने विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र की भाषा और संस्कृति को राष्ट्र के हितों से अधिक महत्व देते हैं। राष्ट्र-निर्माण हेतु यह तब चुनौती बनता है जब यह अलगाववाद या अन्य क्षेत्रों के प्रति शत्रुता पैदा करने लगता है। यह राष्ट्रीय पहचान और भाईचारे की भावना को कमजोर करता है। यदि क्षेत्रीय असंतुलन को ठीक से संबोधित नहीं किया जाए, तो क्षेत्रवाद देश की आंतरिक स्थिरता और अखंडता हेतु गंभीर खतरा उत्पन्न कर सकता है। यह विकास के समान वितरण की मांग पर बल देता है।

162. (A) आरक्षण के लाभों से पिछड़े वर्ग के संपन्न सदस्यों का अपवर्जन।
'क्रीमी लेयर' की अवधारणा का उपयोग ओ.बी.सी. के भीतर उन व्यक्तियों की पहचान हेतु किया जाता है जो आर्थिक रूप से काफी उन्नत हो चुके हैं। मंडल मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि ऐसे संपन्न व्यक्तियों को आरक्षण के लाभों से बाहर रखा जाना चाहिए ताकि वास्तविक लाभ सबसे गरीब सदस्यों तक पहुँच सके। इसके लिए सरकार समय-समय पर आय की सीमा और अन्य मानदंड निर्धारित करती है। यह प्रक्रिया सामाजिक न्याय को अधिक न्यायसंगत बनाती है और संसाधनों के उचित वितरण को सुनिश्चित करती है।

163. (C) कैबिनेट मिशन योजना
भारत की संविधान सभा का गठन 1946 की 'कैबिनेट मिशन योजना' के तहत किया गया था। इस मिशन ने एक ऐसी योजना प्रस्तावित की जिसमें प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से सदस्यों का चयन किया गया। इस योजना ने रियासतों को भी प्रतिनिधित्व प्रदान किया। यद्यपि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच मतभेद थे, परंतु अंततः इसी योजना ने स्वतंत्र भारत हेतु एक संप्रभु संविधान निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। यह ऐतिहासिक कदम भारत के औपनिवेशिक शासन से मुक्ति और लोकतांत्रिक भविष्य की नींव रखने वाला था।

164. (D) संसदीय संप्रभुता
भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता यह है कि यहाँ संसद पूर्णतः संप्रभु नहीं है, बल्कि 'संविधान' सर्वोच्च है। ब्रिटिश प्रणाली में संसद किसी भी कानून को बदल सकती है, परंतु भारत में संसद की शक्तियां संविधान द्वारा सीमित हैं। न्यायपालिका को किसी भी कानून की समीक्षा करने और उसे असंवैधानिक घोषित करने का अधिकार है यदि वह मूल ढांचे का उल्लंघन करता है। लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका और संघीय व्यवस्था भारत की वास्तविक विशेषताएं हैं, जबकि संसदीय संप्रभुता यहाँ केवल एक सीमित अर्थ में ही लागू होती है।

165. (C) सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों दोनों में
बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों दोनों के पास है। अनुच्छेद 32 के तहत नागरिक सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत वे उच्च न्यायालय में आवेदन कर सकते हैं। यह रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा का सबसे प्रभावी माध्यम है, जो अवैध हिरासत को चुनौती देने की अनुमति देता है। उच्च न्यायालयों का रिट क्षेत्राधिकार इस मामले में व्यापक है क्योंकि वे इसे अन्य कानूनी अधिकारों हेतु भी जारी कर सकते हैं। यह नागरिकों की सुरक्षा का सशक्त आधार है।

166. (B) अपनी सहमति प्रदान करेंगे।
संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया में, जब संसद द्वारा विशेष बहुमत से पारित विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो राष्ट्रपति को उस पर सहमति देना अनिवार्य होता है। 24वें संशोधन अधिनियम (1971) ने राष्ट्रपति हेतु यह बाध्यकारी बना दिया कि वे संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर करेंगे। वे न तो इसे अपने पास रोक सकते हैं और न ही पुनर्विचार हेतु वापस भेज सकते हैं। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि संविधान को बदलने की संसद की शक्ति में राष्ट्रपति की वीटो शक्ति बाधा न बने, जिससे विधायी सर्वोच्चता बनी रहे।

167. (D) भारत के राष्ट्रपति
भारत के प्रधानमंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। अनुच्छेद 75 के अनुसार, राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। शपथ ग्रहण समारोह एक औपचारिक संवैधानिक प्रक्रिया है जिसमें प्रधानमंत्री संविधान के प्रति निष्ठा और कर्तव्यों के निष्पक्ष निर्वहन का संकल्प लेते हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होती है। यह प्रक्रिया देश की कार्यपालिका के विधिवत गठन और लोकतांत्रिक शासन की आधारशिला है, जो जवाबदेही सुनिश्चित करती है।

168. (A) राष्ट्रीय सरकार और क्षेत्रीय सरकारें।
संघवाद एक ऐसी राजनीतिक प्रणाली है जिसमें शक्तियों का स्पष्ट विभाजन केंद्रीय सरकार और क्षेत्रीय सरकारों के बीच किया जाता है। दोनों स्तर की सरकारें संविधान से सीधे अपनी शक्तियां प्राप्त करती हैं और अपने अधिकार क्षेत्र में स्वतंत्र होकर कार्य करती हैं। भारत में यह विभाजन सातवीं अनुसूची के माध्यम से किया गया है। संघवाद का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय एकता बनाए रखते हुए क्षेत्रीय विविधताओं और स्थानीय आकांक्षाओं को उचित स्थान एवं स्वायत्तता प्रदान करना है। यह समन्वय और सहयोग पर आधारित शासन का एक प्रभावी मॉडल है।

169. (C) न्याय वितरण प्रणाली को अधिक कुशल, सुलभ और कम खर्चीला बनाना।
न्यायिक सुधारों का प्राथमिक उद्देश्य वर्तमान प्रणाली की खामियों को दूर करना है ताकि नागरिकों को न्याय प्राप्त करने में कम समय और धन खर्च करना पड़े। इसमें अदालतों का आधुनिकीकरण, न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि और तकनीकी नवाचारों का उपयोग शामिल है। इसके साथ ही लोक अदालतों जैसे वैकल्पिक तंत्रों को बढ़ावा देना भी सुधार का हिस्सा है ताकि मुख्य अदालतों पर बोझ कम हो सके। वास्तविक सुधार का अर्थ न्यायपालिका की जवाबदेही बढ़ाना और प्रत्येक नागरिक हेतु न्याय तक समान और सुलभ पहुँच सुनिश्चित करना है।

Click Here to Buy book on Amazon

170. (A) पैरवी
पैरवी या लॉबिंग दबाव समूहों द्वारा अपनाई जाने वाली सबसे प्रभावी विधि है। इसके अंतर्गत समूह के प्रतिनिधि मंत्रियों और उच्च अधिकारियों से सीधे संपर्क कर उन्हें अपने हितों के पक्ष में तर्क और सुझाव प्रदान करते हैं। उनका उद्देश्य नीति निर्माण को अपने अनुकूल प्रभावित करना होता है। यद्यपि अन्य तरीके जैसे धरना भी अपनाए जाते हैं, परंतु पैरवी एक अधिक व्यवस्थित प्रक्रिया है जो सत्ता के गलियारों में सीधे प्रभाव डालने की क्षमता रखती है। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था में विभिन्न समूहों की मांगों को शासन तक पहुँचाने का प्रमुख माध्यम है।

171. (D) जनसंपर्क और आधिकारिक संचार
सरकार द्वारा अपनी नीतियों और योजनाओं के बारे में जनता को सूचित करने हेतु मीडिया का उपयोग जनसंपर्क का हिस्सा है। इसके लिए प्रेस विज्ञप्तियां, विज्ञापन और आधिकारिक घोषणाओं जैसे माध्यमों का उपयोग किया जाता है। इसका उद्देश्य सरकारी कार्यों के प्रति सकारात्मक जनमत तैयार करना और नागरिकों को उपलब्ध सेवाओं की जानकारी देना है। यह लोकतंत्र में पारदर्शिता और सूचना के निरंतर प्रवाह हेतु आवश्यक है। हालांकि इसे सरकारी प्रचार और निष्पक्ष समाचार रिपोर्टिंग के बीच स्पष्ट अंतर के साथ देखा जाना चाहिए।

172. (B) केवल I और II
भारतीय राजनीति में जाति का प्रभाव अत्यंत गहरा है और यह मतदान व्यवहार एवं चुनावी रणनीतियों को व्यापक रूप से प्रभावित करता है। राजनीतिक दल प्रायः उम्मीदवारों का चयन जातिगत पहचान के आधार पर करते हैं ताकि विशिष्ट वोट बैंक को साधा जा सके। इसके कारण कई जाति-आधारित क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ है जो अपने समुदाय के हितों हेतु संघर्ष करते हैं। यद्यपि शहरीकरण के साथ कुछ बदलाव आए हैं, परंतु जाति का प्रभाव आज भी सक्रिय है। यह सामाजिक संरचना और राजनीतिक शक्ति के अंतःसंबंध को दर्शाता है।

173. (C) वैधानिक निकाय
राष्ट्रीय महिला आयोग एक 'वैधानिक निकाय' है, न कि संवैधानिक। इसकी स्थापना संसद द्वारा पारित एक कानून, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990, के तहत की गई थी। इस आयोग का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना, उनके विरुद्ध होने वाले भेदभाव की जांच करना और उनके सशक्तिकरण हेतु सरकार को नीतिगत सिफारिशें देना है। चूँकि यह सीधे संविधान द्वारा निर्मित नहीं है, इसलिए इसकी शक्तियां और कार्य संसद द्वारा बनाए गए संबंधित अधिनियम द्वारा ही निर्धारित और सीमित होते हैं।

174. (D) नियंत्रण और संतुलन के साथ सीमित सरकार।
संविधानवाद एक राजनीतिक दर्शन है जो मानता है कि सरकार की शक्तियां संविधान द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर होनी चाहिए ताकि वह निरंकुश न हो सके। इसका मूल उद्देश्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करना है। इसमें कानून का शासन, स्वतंत्र न्यायपालिका और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की गारंटी शामिल है। यदि सरकार नियमों का पालन नहीं करती और मनमाने ढंग से कार्य करती है, तो वहां संविधानवाद का अभाव माना जाता है। यह मर्यादित शासन का आधार है, जो शक्ति के दुरुपयोग को रोकने हेतु अपरिहार्य है।

175. (A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
भारतीय संविधान एक दोहरी राजव्यवस्था स्थापित करता है, जहाँ केंद्र और राज्य स्तर पर सरकारें अपने क्षेत्रों में कार्य करती हैं। हालांकि, संघवाद के विपरीत, भारत में न्यायपालिका का स्वरूप एकीकृत है। इसका अर्थ है कि पूरे देश हेतु कानूनों का एक ही पदानुक्रम है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष पर है। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि देश भर में कानून की व्याख्या और प्रशासन में एकरूपता बनी रहे। यह एकीकृत ढांचा राष्ट्रीय एकता और कानूनी स्थिरता हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावी संवैधानिक विशेषता है।

176. (D) संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करना।
भारत के राष्ट्रपति के पास कार्यकारी और विधायी शक्तियां हैं, जिनमें प्रधानमंत्री की नियुक्ति और आपातकाल की घोषणा शामिल है। हालांकि वे संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करते हैं। संविधान के अनुसार, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति केवल संयुक्त बैठक बुलाने का आदेश जारी करते हैं और आम चुनाव के बाद तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र में संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हैं। यह विधायी प्रक्रिया में उनके औपचारिक और गरिमामय स्थान को प्रदर्शित करने वाला एक संवैधानिक प्रावधान है।

177. (B) सर्वोच्च न्यायालय के दो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु सर्वोच्च न्यायालय का कॉलेजियम मुख्य न्यायाधीश और दो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों से मिलकर बनता है। यह कॉलेजियम राष्ट्रपति को नियुक्ति हेतु सिफारिशें भेजता है। इसके विपरीत, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु कॉलेजियम में मुख्य न्यायाधीश के साथ चार सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होते हैं। यह प्रक्रिया न्यायिक नियुक्तियों में निष्पक्षता और वरिष्ठता के सम्मान को सुनिश्चित करने हेतु बनाई गई है ताकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता अक्षुण्ण रहे और विधिक प्रतिभाओं का उचित चयन हो सके।

178. (A) विभक्त मतदान
'विभक्त मतदान' उस स्थिति को कहते हैं जब कोई मतदाता एक ही चुनावी दौर में अलग-अलग स्तर के चुनावों हेतु अलग-अलग दलों को चुनता है। उदाहरण के लिए, एक मतदाता लोकसभा चुनाव में किसी राष्ट्रीय दल को वोट दे सकता है, परंतु उसी समय विधानसभा चुनाव हेतु किसी क्षेत्रीय दल को प्राथमिकता दे सकता है। यह व्यवहार दर्शाता है कि मतदाता राष्ट्रीय और स्थानीय मुद्दों के बीच स्पष्ट अंतर करने में सक्षम हैं। वे शासन के प्रत्येक स्तर पर विशिष्ट अपेक्षाएं रखते हैं, जो मतदाताओं की बढ़ती राजनीतिक परिपक्वता को दर्शाता है।

179. (C) 1947 में देश का विभाजन।
1947 में विभाजन के तुरंत बाद भारत में राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या अत्यंत चुनौतीपूर्ण हो गई थी। सांप्रदायिक हिंसा,

NODIA

विस्थापन और करोड़ों शरणार्थियों के पुनर्वास ने राष्ट्र की एकता हेतु संकट पैदा कर दिया था। इसके साथ ही रियासतों का भारतीय संघ में विलय सुनिश्चित करना भी एक विशाल कार्य था। इस कठिन दौर में राष्ट्र-निर्माण का मुख्य उद्देश्य विभिन्न धार्मिक और क्षेत्रीय विविधताओं के बीच विश्वास बहाल करना और धर्मनिरपेक्ष भारत की नींव को मजबूत करना था। यह अवधि देश की अखंडता सुरक्षित रखने हेतु निर्णायक साबित हुई।

180. (A) P-3, Q-1, R-2, S-4
जयप्रकाश नारायण 'संपूर्ण क्रांति' के विचार से जुड़े थे, जिन्होंने 1970 के दशक में लोकतंत्र की रक्षा हेतु आंदोलन चलाया। ई.वी. रामास्वामी नायकर ने तमिलनाडु में आत्म-सम्मान आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसका उद्देश्य जातिगत भेदभाव को समाप्त करना था। डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने 'जाति का विनाश' के माध्यम से सामाजिक समानता की वकालत की। महात्मा गांधी ने 'ग्राम स्वराज' की अवधारणा प्रस्तुत की, जिसमें आत्मनिर्भर गांवों को देश की प्रगति का आधार माना गया था। ये विचार भारतीय सामाजिक और राजनीतिक दर्शन के आधार स्तंभ रहे हैं।

181. (C) संसदीय प्राधिकरण
भारत की आकस्मिकता निधि अनुच्छेद 267 के तहत स्थापित की गई है। यह निधि राष्ट्रपति के पास होती है, जो कार्यपालिका को अप्रत्याशित व्यय करने की अनुमति देती है जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो। हालांकि, इस निधि से किए गए किसी भी खर्च हेतु बाद में संसद का अनुमोदन या 'संसदीय प्राधिकरण' प्राप्त करना अनिवार्य होता है। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि आपातकालीन स्थिति में धन की कमी न हो, परंतु साथ ही सार्वजनिक वित्त पर संसद का अंतिम और सर्वोच्च नियंत्रण भी बना रहे, जो लोकतांत्रिक जवाबदेही हेतु आवश्यक है।

182. (B) कानून की वास्तविक प्रकृति और चरित्र यह पता लगाने के लिए कि वह किस सूची के अंतर्गत आता है।
'सार और तत्व का सिद्धांत' न्यायपालिका द्वारा तब उपयोग किया जाता है जब किसी कानून की विधायी क्षमता पर प्रश्न उठाया जाता है। यदि कोई विधानमंडल अपनी शक्ति के बाहर के विषय पर कानून बनाता है, तो न्यायालय यह देखता है कि उस कानून का मुख्य उद्देश्य क्या है। यदि कानून का मुख्य भाग उस सूची के अंतर्गत आता है जिसके लिए वह विधानमंडल अधिकृत है, तो उसे केवल इसलिए अवैध नहीं ठहराया जा सकता कि वह गलती से किसी अन्य सूची के विषय को स्पर्श करता है। यह सिद्धांत शक्तियों के वितरण में लचीलापन लाता है।

183. (D) अनुच्छेद 368 - युद्ध के कारण आपातकाल
अनुच्छेद 368 का संबंध संविधान संशोधन की शक्ति से है, न कि किसी आपातकाल से। युद्ध या बाहरी आक्रमण के कारण लगने वाले 'राष्ट्रीय आपातकाल' का प्रावधान अनुच्छेद 352 में दिया गया है। अन्य विकल्प सही हैं; अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन और अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। यह स्पष्ट अंतर संविधान के विभिन्न आपातकालीन तंत्रों और उनकी विशिष्ट कार्यप्रणाली को समझने हेतु आवश्यक है। अनुच्छेद 368 संविधान को गतिशील बनाने वाला एक महत्वपूर्ण उपकरण है, जो आपातकालीन उपबंधों से पूर्णतः भिन्न और स्वतंत्र प्रक्रिया है।

184. (A) मेनका गांधी मामला
1978 के मेनका गांधी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की व्याख्या में क्रांतिकारी परिवर्तन किया। न्यायालय ने व्यवस्था दी कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को छीनने वाली प्रक्रिया न केवल 'विधि द्वारा स्थापित' होनी चाहिए, बल्कि वह 'न्यायपूर्ण और तर्कसंगत' भी होनी चाहिए। इस निर्णय ने 'विधि की उचित प्रक्रिया' के तत्वों को भारतीय न्यायशास्त्र में समाहित कर दिया। इसने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को अनुच्छेद 21 का अभिन्न अंग बनाया, जिससे नागरिकों के अधिकारों को राज्य की मनमानी कार्रवाइयों से अधिक विधिक सुरक्षा प्राप्त हुई।

185. (A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
भारतीय संविधान ब्रिटिश और अमेरिकी प्रणालियों का अनूठा समन्वय है। ब्रिटिश प्रणाली में संसद सर्वोच्च है, जबकि अमेरिका में न्यायपालिका को सर्वोच्चता प्राप्त है। भारत में संसद के पास संशोधन की शक्ति है, परंतु न्यायपालिका यह सुनिश्चित करती है कि ये संशोधन संविधान की 'मूल संरचना' को नष्ट न करें। यदि कोई कानून संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय उसे अमान्य कर सकता है। यह 'नियंत्रण और संतुलन' की व्यवस्था है, जो शासन के किसी भी अंग को निरंकुश होने से प्रभावी ढंग से रोकती है।

186. (A) निर्धनों और वंचितों के अधिकार।
जनहित याचिका (पी.आई.एल.) का सबसे महत्वपूर्ण योगदान न्याय के द्वार उन लोगों हेतु खोलना रहा है जो गरीबी या सामाजिक पिछड़ेपन के कारण स्वयं न्यायालय नहीं जा सकते थे। इसने विधिक अधिकारों के संकीर्ण दायरे को तोड़कर सामाजिक न्याय को प्राथमिकता दी है। पी.आई.एल. के माध्यम से कोई भी जागरूक नागरिक सार्वजनिक हित के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। इसने बंधुआ मजदूरी और पर्यावरण प्रदूषण जैसे गंभीर मुद्दों को सुलझाने में असाधारण सफलता प्राप्त की है, जिससे न्याय प्रक्रिया अधिक समावेशी और जनोन्मुखी हुई है।

187. (D) पश्चिम बंगाल
अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (ए.आई.टी.सी.) मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित एक अत्यंत प्रभावशाली क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। ममता बनर्जी के नेतृत्व में इस दल ने राज्य की राजनीति में अपनी मजबूत पकड़ बनाई है। यद्यपि इसे राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त रहा है, परंतु इसकी प्राथमिक शक्ति और जनाधार पश्चिम बंगाल की विशिष्ट भाषाई पहचान और स्थानीय मुद्दों पर आधारित है। क्षेत्रीय दल के रूप में इसने केंद्र-राज्य संबंधों में पश्चिम बंगाल के हितों को प्रमुखता से उठाने और क्षेत्रीय अस्मिता को संरक्षित करने में भूमिका निभाई है।

Downloaded from www.pdf.tube

152. (A) यह संविधान के मूल दर्शन और मौलिक मूल्यों को समाहित करती है।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना इसके उद्देश्यों और आदर्शों का दर्पण है। यह घोषित करती है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य है। प्रस्तावना ही न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे मूलभूत मूल्यों को परिभाषित करती है। हालांकि यह विधायिका हेतु शक्ति का प्रत्यक्ष स्रोत नहीं है, परंतु यह संविधान की व्याख्या में प्रकाश स्तंभ का कार्य करती है। 'समाजवादी' और 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, जो इसके विकसित होते स्वरूप और सामाजिक प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

153. (C) एक निचली अदालत को उसके क्षेत्राधिकार से बाहर जाने से रोकने के लिए।
'प्रतिषेध' की रिट उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत या अर्ध-न्यायिक निकाय को तब जारी की जाती है जब वह अपने कानूनी क्षेत्राधिकार का उल्लंघन कर रही हो। इसका मुख्य उद्देश्य निचली अदालत को ऐसी कार्यवाही से रोकना है जिसके लिए वह कानूनी रूप से अधिकृत नहीं है। यह रिट केवल न्यायिक या अर्ध-न्यायिक अधिकारियों के विरुद्ध ही जारी की जा सकती है। यह 'निवारक' प्रकृति की होती है, क्योंकि यह त्रुटि होने से पूर्व ही उसे रोककर न्याय व्यवस्था की शुद्धता और मर्यादा को अक्षुण्ण बनाए रखती है।

154. (A) शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया।
2002 का 86वां संशोधन अधिनियम सामाजिक सुधार की दिशा में ऐतिहासिक कदम था। इसके माध्यम से अनुच्छेद 21A जोड़ा गया, जिसने 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों हेतु निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया। इसके साथ ही अनुच्छेद 45 में भी बदलाव किया गया और माता-पिता हेतु एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। यह संशोधन राष्ट्र के बौद्धिक विकास और भविष्य की पीढ़ी के सशक्तिकरण हेतु एक मजबूत आधार तैयार करने के उद्देश्य से किया गया था, जो सामाजिक न्याय हेतु अनिवार्य है।

155. (A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
भारत के राष्ट्रपति को केवल महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा ही हटाया जा सकता है, जो एक औपचारिक विधिक प्रक्रिया है। अनुच्छेद 61 के अनुसार, महाभियोग का एकमात्र आधार 'संविधान का उल्लंघन' है। यह प्रक्रिया संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत की आवश्यकता के कारण अत्यंत जटिल बनाई गई है ताकि पद की गरिमा और सुरक्षा बनी रहे। अब तक भारत के इतिहास में किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चलाया गया है, जो हमारे संवैधानिक लोकतंत्र की स्थिरता और विधिक मर्यादा का श्रेष्ठ प्रमाण है।

156. (B) प्रश्न काल के तुरंत बाद का समय।
'शून्य काल' एक अनूठा संसदीय उपकरण है जो प्रश्न काल की समाप्ति के तुरंत बाद शुरू होता है। यह दोपहर 12 बजे शुरू होने के कारण शून्य काल कहलाता है। इस दौरान सदस्य बिना किसी पूर्व सूचना के सार्वजनिक महत्व के अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे उठा सकते हैं। यद्यपि इसका उल्लेख संसदीय नियमों में नहीं है, परंतु 1960 के दशक से यह एक परंपरा बन गई है जो जनता की तत्काल समस्याओं को सदन के पटल पर लाने का अवसर देती है। यह विधायी नियंत्रण का एक अत्यंत जीवंत और सक्रिय माध्यम है।

157. (C) अनुच्छेद 3
संविधान का अनुच्छेद 3 संसद को देश के भीतर राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, नए राज्य बनाने या किसी राज्य का नाम बदलने की शक्ति प्रदान करता है। इसके लिए संसद को केवल साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। ऐसा विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही पेश किया जा सकता है। यद्यपि संबंधित राज्य विधानमंडल को विचार व्यक्त करने हेतु भेजा जाता है, परंतु संसद उनके विचारों को मानने हेतु बाध्य नहीं है। यह अनुच्छेद भारतीय संघ के लचीले स्वरूप और केंद्र की सर्वोपरि शक्ति को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है।

158. (D) सलाहकार क्षेत्राधिकार
अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को सार्वजनिक महत्व के किसी विधिक प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय की राय मांगने का अधिकार है। इसे न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय अपनी सलाह देने हेतु बाध्य नहीं है, और राष्ट्रपति भी उस सलाह को मानने हेतु विवश नहीं हैं। यह प्रक्रिया सरकार को जटिल कानूनी मुद्दों पर उच्च-स्तरीय विधिक मार्गदर्शन प्राप्त करने में सहायता करती है, जिससे संभावित कानूनी विवादों या संवैधानिक संकटों को टाला जा सके। यह न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच सहयोग का तंत्र है।

159. (A) समाज का एक विशेष धार्मिक या जातीय वर्ग।
सांप्रदायिक दबाव समूह वे संगठन हैं जो किसी विशेष धार्मिक, जातीय या भाषाई वर्ग के हितों की रक्षा हेतु कार्य करते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य अपने समुदाय हेतु विशेष लाभ, अधिकार या संरक्षण प्राप्त करना है। ये समूह धार्मिक पहचान के आधार पर राजनीतिक लामबंदी करते हैं और सरकार की उन नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं जो उनके समुदाय से संबंधित होती हैं। बहुलवादी समाज में ये समूह कभी-कभी हितों के टकराव का कारण बन सकते हैं, जिससे राष्ट्रीय एकीकरण और सामाजिक सद्भाव प्रभावित होता है।

160. (A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
स्वतंत्र चुनाव जीवंत लोकतंत्र की अनिवार्य शर्त है। इसे सुनिश्चित करने हेतु संविधान ने निर्वाचन आयोग को एक स्वायत्त निकाय बनाया है। यदि चुनावी तंत्र कार्यपालिका के सीधे नियंत्रण में होता, तो सत्ता पक्ष द्वारा चुनावों में हेरफेर की आशंका बनी रहती। निर्वाचन आयोग की संवैधानिक स्वतंत्रता उसे बिना किसी राजनीतिक दबाव के अपनी जिम्मेदारी निभाने और जनमत की निष्पक्षता बनाए रखने की शक्ति प्रदान करती है। अतः कारण पूरी तरह से अभिकथन का समर्थन करता है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा हेतु अपरिहार्य है।

NODIA

के साझा सरोकारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि इस सूची के विषय पर केंद्र और राज्य के कानूनों में टकराव होता है, तो केंद्रीय कानून को वरीयता प्राप्त होती है। यह व्यवस्था भारतीय संघवाद में समन्वय और एकरूपता बनाए रखने में सहायक होती है, जिससे राष्ट्रीय और क्षेत्रीय हितों का सामंजस्य बना रहता है और सुचारु शासन सुनिश्चित होता है।

197. (C) जनहित याचिका
'वाद का अधिकार' के पारंपरिक नियम के अनुसार केवल वही व्यक्ति न्यायालय जा सकता था जिसका अपना कानूनी अधिकार प्रभावित हुआ हो। सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका (पी. आई.एल.) के माध्यम से इस नियम को उदार बनाया, जिससे समाज का कोई भी जागरूक व्यक्ति सार्वजनिक हित के मामलों में उन लोगों की ओर से न्याय की गुहार लगा सकता है जो स्वयं ऐसा करने में असमर्थ हैं। इस न्यायिक नवाचार ने न्यायालय को सामाजिक परिवर्तन के एक सक्रिय साधन के रूप में स्थापित किया और न्याय तक पहुँच को व्यापक एवं समावेशी बनाया है।

198. (B) छात्रों के एक समूह द्वारा स्वतः स्फूर्त विरोध।
गैर-साहचर्य दबाव समूह वे होते हैं जो किसी औपचारिक संगठन के बिना अचानक उभरते हैं। इनका आधार अक्सर साझा तात्कालिक चिंताएं होती हैं। उदाहरण हेतु, जब छात्र किसी प्रशासनिक निर्णय के विरोध में स्वतः रैलियां करते हैं, तो वे एक गैर-साहचर्य समूह के रूप में कार्य करते हैं। इनके विपरीत, ट्रेड यूनियन सुव्यवस्थित संगठन होते हैं। गैर-साहचर्य समूह अपनी अनौपचारिक प्रकृति के कारण लचीले होते हैं, लेकिन उनकी प्रभावशीलता अक्सर अल्पकालिक होती है। ये समूह जनमत को त्वरित रूप से प्रभावित करने और शासन का ध्यान आकर्षित करने में सक्षम होते हैं।

199. (D) एक निर्वाचन क्षेत्र में पात्र मतदाताओं की सूची।
'मतदाता सूची' उस आधिकारिक दस्तावेज़ को कहते हैं जिसमें एक निर्वाचन क्षेत्र में मतदान हेतु पात्र सभी व्यक्तियों के नाम और विवरण शामिल होते हैं। भारत में, 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी नागरिक, जो विधिक रूप से अयोग्य नहीं हैं, इस सूची में नाम दर्ज कराने के हकदार हैं। निर्वाचन आयोग का यह प्राथमिक कर्तव्य है कि वह प्रत्येक चुनाव से पूर्व इस सूची को अद्यतन करे ताकि कोई भी पात्र मतदाता अपने लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित न रहे। यह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया की पहली और बुनियादी अनिवार्य शर्त है।

200. (A) निम्न स्थिति की निष्क्रिय स्वीकृति से एक मुखर राजनीतिक चेतना की ओर
'दलित' पहचान का उदय भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण सामाजिक परिवर्तन का प्रतीक है। यह शब्द सदियों से व्याप्त शोषण के विरुद्ध एक सक्रिय प्रतिरोध और मुखर चेतना को प्रदर्शित करता है। यह उस पारंपरिक मानसिकता से बदलाव है जहाँ भेदभाव को भाग्य मानकर स्वीकार कर लिया जाता था। आधुनिक दलित राजनीति आत्म-सम्मान, समानता और सत्ता में समान भागीदारी की मांग पर आधारित है, जिसने लोकतंत्र को अधिक समावेशी और गतिशील बनाया है। इसके कारण हाशिए के वर्गों का सशक्तिकरण हुआ है और वे निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदार बने हैं।

201. (C) समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता
42वें संशोधन अधिनियम 1976 ने नीति निदेशक तत्वों में अनुच्छेद 39A जोड़ा। यह राज्य को सुनिश्चित करने का निर्देश देता है कि कानूनी प्रणाली न्याय को बढ़ावा दे और आर्थिक अक्षमताओं के कारण कोई नागरिक न्याय से वंचित न रहे। इसके लिए 'निःशुल्क विधिक सहायता' की व्यवस्था करना राज्य का कर्तव्य है। यह संशोधन सामाजिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त करने और कानून के शासन को समाज के सबसे कमजोर तबकों तक पहुँचाने की दिशा में प्रगतिशील कदम था, जो विधिक समानता के संवैधानिक आदर्श को व्यावहारिक बनाता है।

202. (A) कुल सदस्य संख्या का दसवां भाग।
गणपूर्ति सदन की वह न्यूनतम सदस्य संख्या है जिसकी उपस्थिति में सदन की कार्यवाही कानूनी रूप से संचालित की जा सकती है। अनुच्छेद 100 के अनुसार, लोकसभा और राज्यसभा दोनों हेतु गणपूर्ति सदन की कुल सदस्य संख्या का दसवां भाग निर्धारित की गई है। यदि सदन में इस संख्या से कम सदस्य उपस्थित होते हैं, तो अध्यक्ष का कर्तव्य है कि वे सदन को स्थगित कर दें या कार्यवाही तब तक रोक दें जब तक गणपूर्ति पूरी न हो जाए। यह विधायी प्रक्रिया की गंभीरता और सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने वाला एक अनिवार्य नियम है।

203. (D) राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 द्वारा
भारत में क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के माध्यम से की गई थी। ये परिषदें वैधानिक निकाय हैं, संवैधानिक नहीं। इनका मुख्य उद्देश्य राज्यों के बीच और केंद्र एवं राज्यों के बीच सहयोग और अंतर-राज्य सद्भाव को बढ़ावा देना है। देश को पाँच क्षेत्रों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक के लिए एक परिषद बनाई गई है। केंद्रीय गृह मंत्री इन परिषदों के अध्यक्ष होते हैं। ये परिषदें आर्थिक नियोजन और सीमा विवादों जैसे साझा मुद्दों पर चर्चा हेतु एक महत्वपूर्ण और प्रभावी मंच प्रदान करती हैं।

204. (B) गुवाहाटी उच्च न्यायालय
गुवाहाटी उच्च न्यायालय भारत के उन न्यायालयों में से एक है जिसका क्षेत्राधिकार एक से अधिक राज्यों पर विस्तृत है। वर्तमान में इसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश शामिल हैं। प्रारंभ में इसका दायरा और भी व्यापक था। यह व्यवस्था न्यायिक प्रशासन की दक्षता और भौगोलिक निकटता को ध्यान में रखते हुए की गई है। एकीकृत न्यायपालिका के तहत ये न्यायालय विभिन्न राज्यों हेतु कानून की व्याख्या और अधिकारों के रक्षक के रूप में अपनी भूमिका निष्पक्ष रूप से निभाते हैं, जो क्षेत्रीय न्याय सुनिश्चित करता है।

Click Here to Buy book on Amazon

अधिकारों का उल्लंघन न करें। भारत में न तो संसद निरंकुश है और न ही न्यायपालिका विधायी प्रक्रियाओं में पूर्णतः हस्तक्षेप कर सकती है। यह 'नियंत्रण और संतुलन' का उत्कृष्ट उदाहरण है जो देश की लोकतांत्रिक स्थिरता और कानून के शासन को सशक्त बनाता है।

273. (B) 44वां संशोधन अधिनियम
भारतीय संविधान में मूलतः संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 19 और 31 के तहत एक मौलिक अधिकार था। सामाजिक असमानताओं को दूर करने और भूमि सुधारों को प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु, 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा इसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। अब यह संविधान के भाग XII में अनुच्छेद 300A के तहत केवल एक विधिक अधिकार है। इस परिवर्तन का अर्थ है कि राज्य अब कानूनी प्रक्रिया का पालन करके संपत्ति का अधिग्रहण कर सकता है, और नागरिक इसके लिए मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का दावा नहीं कर सकते।

274. (A) कम से कम आधे राज्यों के।
संघीय ढांचे की सुरक्षा हेतु अनुच्छेद 368 में विशेष प्रक्रिया निर्धारित है। यदि संसद उन प्रावधानों में संशोधन करना चाहती है जो राज्यों के हितों या संघीय संतुलन को प्रभावित करते हैं (जैसे सातवीं अनुसूची), तो संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत के साथ-साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों की सहमति अनिवार्य है। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि केंद्र सरकार राज्यों की शक्तियों या संघीय संरचना के साथ एकतरफा परिवर्तन न कर सके। यह प्रावधान भारतीय संघवाद की अखंडता और विभिन्न इकाइयों के बीच शक्ति संतुलन हेतु अपरिहार्य है।

275. (A) केवल I और II
प्रधानमंत्री की भूमिका शासन के शीर्ष पर एक 'लिंक' के समान है। वे मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णयों की जानकारी राष्ट्रपति को देते हैं, जो संवैधानिक उत्तरदायित्व का हिस्सा है। वे विधायी कार्यों में भी राष्ट्रपति को सलाह देते हैं, जैसे संसद का सत्र बुलाना। हालांकि, न्यायिक नियुक्तियों में उनकी कोई सीधी या अंतिम भूमिका नहीं होती; वह प्रक्रिया मुख्य रूप से कॉलेजियम और राष्ट्रपति के बीच होती है। प्रधानमंत्री की वास्तविक शक्ति उनके राजनीतिक नेतृत्व और मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण में निहित है, जो उन्हें व्यवस्था का सबसे शक्तिशाली पद बनाती है।

276. (D) उत्तर-पूर्व के राज्यों जैसे कुछ राज्यों के लिए विशिष्ट संवैधानिक प्रावधान।
'असममित संघवाद' का अर्थ है कि संघ के सभी राज्यों के पास समान शक्तियां या दर्जे नहीं होते। भारत में, अनुच्छेद 371 के तहत नागालैंड, मिजोरम और असम जैसे राज्यों को उनकी अद्वितीय सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के कारण विशेष दर्जा और संरक्षण प्रदान किया गया है। यह व्यवस्था उन राज्यों की विशिष्ट जरूरतों को पूरा करने और उन्हें भारतीय संघ में स्वेच्छा से एकीकृत करने हेतु की गई है। यह दर्शाता है कि भारतीय संघवाद कठोर नहीं है, बल्कि वह राष्ट्रीय एकता बनाए रखने हेतु क्षेत्रीय विविधताओं को समायोजित करने में लचीला है।

277. (C) सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन याचिका खारिज किए जाने के बाद।
'सुधारात्मक याचिका' भारतीय न्यायपालिका का अंतिम विधिक उपाय है जो न्याय की गंभीर विफलता को रोकने हेतु विकसित किया गया है। यह याचिका तब दायर की जा सकती है जब सर्वोच्च न्यायालय अपनी 'पुनर्विलोकन याचिका' को भी खारिज कर देता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी तकनीकी त्रुटि के कारण किसी व्यक्ति को अन्याय का सामना न करना पड़े। यह याचिका केवल अत्यंत विरल और गंभीर मामलों में ही स्वीकार की जाती है और इसकी सुनवाई प्रायः बंद कमरे में होती है। यह सर्वोच्च न्यायालय की न्याय के प्रति अंतिम प्रतिबद्धता है।

278. (B) पर्यावरण आंदोलन।
1970 के दशक में उत्तराखंड में शुरू हुआ 'चिपको आंदोलन' आधुनिक भारत का अत्यंत प्रभावशाली पर्यावरण आंदोलन था। स्थानीय ग्रामीणों, विशेषकर महिलाओं ने पेड़ों को कटने से बचाने हेतु उनसे चिपककर अहिंसक प्रतिरोध किया। इस आंदोलन ने न केवल वनों की अंधाधुंध कटाई पर अंकुश लगाया, बल्कि पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण और सामुदायिक अधिकारों के प्रति वैश्विक जागरूकता पैदा की। 'पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था है' का इसका नारा पर्यावरण संरक्षण के इतिहास में अमर हो गया। इसने सिद्ध किया कि जनता की संगठित शक्ति प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करने में सक्षम है।

279. (D) मतदान प्रक्रिया की पारदर्शिता और सत्यापन योग्यता को बढ़ाना।
वी.वी.पी.ए.टी. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ जुड़ी एक स्वतंत्र प्रणाली है। जब कोई मतदाता वोट देता है, तो यह मशीन एक कागजी पर्ची उत्पन्न करती है जो मतदाता को कुछ सेकंड हेतु दिखाई देती है, जिससे वह पुष्टि कर सकता है कि उसका वोट सही उम्मीदवार को गया है। यह पर्ची बाद में एक सुरक्षित बॉक्स में गिर जाती है। यह चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता और पारदर्शिता को अत्यधिक बढ़ाता है। विवाद की स्थिति में इन पर्चियों की गणना करके ई.वी.एम. के परिणामों का सत्यापन किया जा सकता है, जो निष्पक्ष चुनाव हेतु अनिवार्य है।

280. (A) क्षेत्रवाद और अंतर-राज्य विवाद
यद्यपि 1956 के भाषाई पुनर्गठन ने भाषाई तनाव को काफी हद तक कम किया, परंतु इसने कुछ नई चुनौतियों को भी जन्म दिया। राज्यों के निर्माण के बाद सीमाओं के निर्धारण, नदी जल के बंटवारे और राजधानी के स्वामित्व को लेकर पड़ोसी राज्यों के बीच 'क्षेत्रवाद' और विवाद बढ़ गए। उदाहरण हेतु, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद या विभिन्न राज्यों के बीच जल विवाद इसी प्रक्रिया के परिणामस्वरूप और मुखर हुए। यह दर्शाता है कि राष्ट्र-निर्माण एक सतत प्रक्रिया है जहाँ एक समस्या का समाधान अक्सर नई प्रशासनिक और राजनीतिक चुनौतियां पेश करता है।

NODIA

है कि संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। इसका मुख्य कारण यह है कि संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक उस पर राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त न हो जाए। यह विधायी प्रक्रिया में उनके केंद्रीय संवैधानिक महत्व और विधायी शक्तियों के अंतिम प्रमाणीकरण की अनिवार्य भूमिका को दर्शाता है।

214. (B) भाग XII
भारतीय संविधान के भाग XII (अनुच्छेद 264-300) में संघ और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों का विस्तृत विवरण है। इसमें करों के वितरण, अनुदानों के प्रावधान और वित्त आयोग की शक्तियों का उल्लेख है। यह भाग सुनिश्चित करता है कि केंद्र और राज्यों के पास कार्यों को पूरा करने हेतु पर्याप्त संसाधन हों। यह संघीय ढांचे की आर्थिक स्थिरता और राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता हेतु महत्वपूर्ण संवैधानिक आधार प्रदान करता है, जिससे सहकारी संघवाद का मार्ग प्रशस्त होता है और विभिन्न स्तरों पर वित्तीय जवाबदेही भी सुनिश्चित होती है।

215. (C) न्यायिक और अर्ध-न्यायिक प्राधिकारी
'उत्प्रेषण' की रिट उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालतों या उन अधिकारियों के विरुद्ध जारी की जाती है जो अर्ध-न्यायिक कार्य करते हैं। इस रिट का उद्देश्य किसी मामले के रिकॉर्ड को समीक्षा हेतु ऊपर मंगाना है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि निचली अदालत ने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन नहीं किया है। यह रिट तब जारी होती है जब निचली अदालत निर्णय दे चुकी हो। यह न्यायिक व्यवस्था में त्रुटियों को सुधारने और विधिक प्रक्रिया की शुद्धता बनाए रखने का प्रभावी साधन है, जिससे कानून का शासन सशक्त होता है।

216. (A) P-3, Q-1, R-2, S-4
विभिन्न देशों की दलीय प्रणालियाँ उनकी राजनीतिक संरचना को दर्शाती हैं। चीन में एक-दलीय प्रणाली है। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रमुख रूप से द्वि-दलीय प्रणाली है। भारत में 1989 के बाद बहु-दलीय प्रणाली का उदय हुआ, जहाँ गठबंधन सरकारें बनीं। वहीं, स्वतंत्रता के बाद के शुरुआती वर्षों में भारत में कांग्रेस के प्रभुत्व वाली 'प्रभावी दलीय प्रणाली' थी। यह वर्गीकरण लोकतंत्र के विविध रूपों और राजनीतिक सत्ता के वितरण के अलग-अलग प्रतिरूपों को स्पष्ट करता है, जो समाज की राजनीतिक परिपक्वता और विविधता को दर्शाते हैं।

217. (C) स्वामित्व का संकेंद्रण और पेड न्यूज के मुद्दे।
भारतीय मीडिया हेतु बड़ी चुनौती बड़े औद्योगिक घरानों द्वारा मीडिया संस्थानों का स्वामित्व लेना है, जिससे निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है। 'पेड न्यूज' की समस्या पत्रकारिता की नैतिकता को गंभीर क्षति पहुँचाती है। यह प्रवृत्ति पाठकों को गुमराह करती है और लोकतांत्रिक चर्चाओं की गुणवत्ता कम करती है। मीडिया का व्यवसायिक हित अक्सर सार्वजनिक हित पर हावी हो जाता है, जो एक स्वतंत्र प्रहरी के रूप में उसकी भूमिका के विरुद्ध है। सूचना की शुचिता बनाए रखने हेतु इस प्रकार की व्यावसायिक प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाना अनिवार्य है।

218. (A) राजनीतिक समाजशास्त्र
चुनावी व्यवहार का अध्ययन मुख्य रूप से 'राजनीतिक समाजशास्त्र' का विषय है। यह अनुशासन इस बात का विश्लेषण करता है कि समाज की संरचना, जैसे जाति, वर्ग और धर्म, राजनीतिक निर्णयों को कैसे प्रभावित करती है। यह राजनीति और समाज के बीच अंतःसंबंधों की जांच करता है। मतदाताओं की प्रेरणाएं, सामाजिक समूहों की वफादारी और राजनीतिक संस्थाओं के प्रति दृष्टिकोण इस अध्ययन के केंद्र में होते हैं। यह क्षेत्र चुनावों के माध्यम से समाज में हो रहे सूक्ष्म और व्यापक राजनीतिक परिवर्तनों को समझने और भविष्य के रुझानों का आकलन करने में सहायक है।

219. (D) बजट के लिंग-विभेदित प्रभाव का आकलन करना।
'जेंडर बजटिंग' का तात्पर्य यह जांचना है कि सरकारी खर्च और कर नीतियां पुरुषों और महिलाओं को अलग-अलग रूप में कैसे प्रभावित करती हैं। इसका उद्देश्य संसाधनों के आवंटन में व्याप्त लैंगिक असमानताओं को दूर करना है ताकि विकास के लाभ महिलाओं तक भी प्रभावी ढंग से पहुँचें। यह लैंगिक समानता प्राप्त करने और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु एक महत्वपूर्ण वित्तीय उपकरण है। यह सामाजिक न्याय के संवैधानिक लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करता है और यह सुनिश्चित करता है कि सार्वजनिक धन का वितरण न्यायपूर्ण हो।

220. (B) सरदार वल्लभभाई पटेल
स्वतंत्रता के समय 565 रियासतों का विलय राष्ट्र-निर्माण की सबसे बड़ी चुनौती थी। सरदार वल्लभभाई पटेल ने अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति और कूटनीतिक कौशल से इस कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न किया। उनकी दूरदर्शिता के कारण ही भारत का भौगोलिक और राजनीतिक एकीकरण संभव हुआ, जिसके लिए उन्हें 'लौह पुरुष' कहा जाता है। उन्होंने रियासतों को शांतिपूर्ण ढंग से विलय हेतु राजी किया। उनका यह योगदान आधुनिक भारतीय राष्ट्र की नींव रखने में सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना है, जिसने एक अखंड और शक्तिशाली भारत के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया।

221. (C) भारत के लोग
संविधान की प्रस्तावना "हम भारत के लोग" शब्दों से प्रारंभ होती है, जो यह स्पष्ट करती है कि भारत की संप्रभुता का अंतिम स्रोत जनता है। इसका अर्थ है कि संविधान अपनी शक्ति सीधे जनता से प्राप्त करता है और सरकार का अस्तित्व उनकी सहमति पर आधारित है। भारत एक लोकतंत्र है जहाँ जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है। यह घोषणा किसी भी बाहरी सत्ता या राजतंत्र की सर्वोच्चता को पूरी तरह नकारती है और राष्ट्र के भाग्य का निर्माता देश के नागरिकों को मानती है, जो लोकतांत्रिक आदर्श है।

222. (D) मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निदेशक तत्व
मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्वों को अक्सर 'संविधान की अंतरात्मा' कहा जाता है। जहाँ मौलिक अधिकार नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, वहीं नीति निदेशक तत्व एक कल्याणकारी

NODIA

205. (C) जमींदारों को दिए जाने वाले फसल के हिस्से को आधे से घटाकर एक-तिहाई करना।
तेभागा आंदोलन (1946-47) बंगाल में एक ऐतिहासिक किसान संघर्ष था। 'तेभागा' का अर्थ है तीन भाग; बटाईदार किसानों की मुख्य मांग थी कि फसल का दो-तिहाई हिस्सा उन्हें मिलना चाहिए और जमींदारों का हिस्सा आधा से घटकर केवल एक-तिहाई होना चाहिए। यह आंदोलन ग्रामीण अर्थव्यवस्था में व्याप्त शोषण और जमींदारी व्यवस्था के विरुद्ध था। यद्यपि इसे स्वतंत्रता पूर्व कुचल दिया गया, परंतु इसने भविष्य के भूमि सुधारों और किसान चेतना के विकास हेतु एक मजबूत वैचारिक धरातल तैयार किया, जिससे ग्रामीण शक्ति संतुलन में परिवर्तन आया।

206. (D) यह कम से कम दस वर्षों से अस्तित्व में है।
निर्वाचन आयोग द्वारा किसी दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता देने हेतु कई शर्तें हैं, परंतु दल की उम्र (जैसे दस वर्ष) इसमें शामिल नहीं है। प्रमुख शर्तों में शामिल है कि दल को चार राज्यों में राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त हो, या वह तीन राज्यों से लोकसभा की दो प्रतिशत सीटें जीते, या चार राज्यों में वैध मतों का छह प्रतिशत प्राप्त करे। ये मानदंड दल के वास्तविक जनाधार और व्यापक राजनीतिक प्रभाव को सुनिश्चित करने हेतु बनाए गए हैं, जो लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा की गुणवत्ता बनाए रखते हैं।

207. (A) क्षेत्रीय आर्थिक असंतुलन के साथ भाषाई और सांस्कृतिक विविधता
स्वतंत्रता के बाद क्षेत्रवाद के उदय का प्राथमिक कारण विभिन्न राज्यों के बीच विकास का असमान स्तर था। जब कुछ क्षेत्रों ने प्रगति की और अन्य पिछड़े रह गए, तो आर्थिक उपेक्षा की भावना ने क्षेत्रीय पहचान को मुखर बनाया। इसके साथ ही भाषाई और सांस्कृतिक विविधता ने भी लोगों को अपनी विशिष्ट पहचान के प्रति जागरूक किया। क्षेत्रीय भाषाओं को संरक्षित करने की आकांक्षा अक्सर राजनीतिक आंदोलनों का रूप ले लेती है। यह विविधता संघवाद हेतु चुनौती और अवसर दोनों है, जो समावेशी विकास और संतुलित क्षेत्रीय प्रगति की मांग करती है।

208. (D) विभिन्न संसदीय प्रक्रियाएं जैसे प्रश्न, प्रस्ताव और वित्तीय नियंत्रण।
संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका पर नियंत्रण हेतु विधायिका कई प्रभावी साधनों का उपयोग करती है। प्रश्न काल के माध्यम से सदस्य मंत्रियों से उनकी नीतियों पर स्पष्टीकरण मांगते हैं। स्थगन प्रस्ताव जैसे माध्यमों से सरकार की विफलताओं की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, बजट पारित करने की प्रक्रिया के दौरान वित्तीय नियंत्रण के माध्यम से संसद यह सुनिश्चित करती है कि सार्वजनिक धन का उपयोग विधिक रुप से किया जाए। ये सभी प्रक्रियाएं सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह और सतर्क बनाए रखने में अत्यंत सहायक और प्रभावी होती हैं।

209. (B) भ्रष्टाचार की रोकथाम
के. संथानम समिति की नियुक्ति 1962 में प्रशासन में भ्रष्टाचार की समस्या का अध्ययन करने हेतु की गई थी। समिति की सिफारिशें अत्यंत प्रभावशाली रहीं, जिनके परिणामस्वरूप 1964 में 'केंद्रीय सतर्कता आयोग' की स्थापना हुई। संथानम समिति ने सरकारी कर्मचारियों के आचरण, प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों को मजबूत करने पर बल दिया था। इसकी रिपोर्ट आज भी भारत में भ्रष्टाचार के विरुद्ध संस्थागत ढांचे के निर्माण में एक बुनियादी आधार स्तंभ मानी जाती है, जो शासन की शुचिता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण है।

210. (A) संयुक्त राज्य अमेरिका
आधुनिक विश्व में 'लिखित संविधान' की अवधारणा को सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनाया था। 1787 में तैयार अमेरिकी संविधान विश्व का सबसे पुराना लिखित राष्ट्रीय संविधान है। इसने संवैधानिक सर्वोच्चता, शक्तियों के पृथक्करण और नागरिकों के अधिकारों की गारंटी जैसे आधुनिक सिद्धांतों की नींव रखी। इसके विपरीत, यूनाइटेड किंगडम का संविधान अलिखित है। अमेरिका के इस सफल प्रयोग ने भारत सहित अनेक देशों को अपने शासन की बुनियादी संरचना को एक स्पष्ट और लिखित दस्तावेज़ के रूप में संहिताबद्ध करने हेतु गहराई से प्रेरित किया था।

211. (B) समानता का अधिकार - उपाधियों का अंत शामिल है
समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18) समाज में विशेषाधिकारों को समाप्त करने का प्रयास करता है। अनुच्छेद 18 के तहत 'उपाधियों का अंत' किया गया है, जिसका अर्थ है कि राज्य सैन्य या शैक्षणिक विशिष्टता के अतिरिक्त कोई अन्य उपाधि प्रदान नहीं करेगा। इसका उद्देश्य नागरिकों के बीच कृत्रिम भेदभाव को मिटाना और समान सामाजिक स्तर सुनिश्चित करना है। यह प्रावधान लोकतंत्र की बुनियादी शर्त है, जो प्रत्येक व्यक्ति को समान नागरिक सम्मान प्रदान करता है। अन्य विकल्प मौलिक अधिकारों की सही श्रेणी या व्याख्या के साथ मेल नहीं खाते हैं।

212. (D) नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना।
भारतीय संविधान में कुछ प्रावधान हैं जिनमें संसद केवल साधारण बहुमत से ही संशोधन कर सकती है। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना (अनुच्छेद 2 और 3) इसी श्रेणी में आते हैं। ऐसे संशोधनों को अनुच्छेद 368 के तहत 'संवैधानिक संशोधन' नहीं माना जाता है। इसके विपरीत, मौलिक अधिकारों में परिवर्तन या राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया में बदलाव हेतु विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। यह व्यवस्था संविधान के लचीलेपन और कठोरता के बीच एक संतुलित समन्वय को दर्शाती है, जो शासन की सुगमता हेतु आवश्यक है।

213. (A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
भारतीय संविधान के अनुसार, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते और न ही उसकी कार्यवाही में भाग लेते हैं। हालांकि, वे संसद के 'अभिन्न अंग' हैं। अनुच्छेद 79 स्पष्ट करता

Downloaded from www.pdf.tube

है। यह समानता के संवैधानिक आदर्श को व्यावहारिक रूप में लागू करने का सबसे सशक्त माध्यम है, जो जन-भागीदारी को सुनिश्चित करता है।

231. (D) जाति, धर्म, भाषा या क्षेत्र सहित साझा पहचान।
'पहचान की राजनीति' का तात्पर्य उन समूहों के राजनीतिक संगठन से है जो अपनी साझा सामाजिक पहचान के आधार पर अधिकारों का दावा करते हैं। इसमें जाति-आधारित आंदोलन या भाषाई गौरव हेतु संघर्ष देखे जाते हैं। यह राजनीति अक्सर ऐतिहासिक उपेक्षा के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में उभरती है। हालांकि यह लोकतंत्र में विभिन्न समूहों की आवाज़ को मजबूती प्रदान करती है, परंतु कभी-कभी इसके कारण समाज में ध्रुवीकरण की संभावना भी बनी रहती है। यह समुदायों को अपनी अस्मिता के प्रति जागरूक करती है और सत्ता में उनकी उचित हिस्सेदारी की मांग उठाती है।

232. (A) भाषा पर आधारित क्षेत्रवाद
1956 में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन भारत की एकता को बनाए रखने की दिशा में दूरदर्शी कदम था। स्वतंत्रता के बाद विभिन्न भाषाई समूहों द्वारा पृथक पहचान हेतु आंदोलनों ने क्षेत्रवाद की भावना को तीव्र कर दिया था। इस समस्या को हल करने हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया, जिससे नए राज्यों का निर्माण हुआ। इस कदम ने क्षेत्रीय आकांक्षाओं को लोकतांत्रिक संतुष्टि प्रदान की और यह सिद्ध किया कि भाषाई विविधता राष्ट्र की एकता हेतु खतरा नहीं बल्कि उसे समृद्ध करने वाला एक महत्वपूर्ण तत्व है।

233. (C) मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार
भारत सरकार अधिनियम 1919 को मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों के रूप में जाना जाता है। इस अधिनियम ने ब्रिटिश भारत में पहली बार 'द्वैध शासन' की शुरुआत की, जिससे प्रशासनिक विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित श्रेणियों में विभाजित किया गया। इसने केंद्र में द्विसदनीय विधायिका और प्रत्यक्ष चुनाव की भी शुरुआत की। यद्यपि ये सुधार भारतीय आकांक्षाओं को पूर्णतः संतुष्ट नहीं कर सके, परंतु इन्होंने देश में उत्तरदायी सरकार के विकास की दिशा में एक क्रमिक संवैधानिक कदम बढ़ाया था। इसने विधायी संस्थानों में भारतीयों की भागीदारी के मार्ग को प्रशस्त किया।

234. (A) यह एक सुदृढ़ एकात्मक झुकाव के साथ संघीय विशेषताओं को जोड़ता है।
भारतीय संविधान को 'अर्ध-संघीय' इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह शक्तियों के विभाजन वाली संघीय व्यवस्था का पालन करते हुए केंद्र को असाधारण शक्तियां देता है। सामान्य समय में यह संघीय रूप में कार्य करता है, परंतु आपातकाल में पूर्णतः एकात्मक बन सकता है। एकल नागरिकता और एकीकृत न्यायपालिका केंद्र के प्रभुत्व को दर्शाती हैं। यह अनूठी संरचना देश की विशाल विविधता को संभालने के साथ-साथ इसकी अखंडता और सुरक्षा को हर हाल में सुनिश्चित करने हेतु तैयार की गई थी। यह राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रीय स्वायत्तता का संतुलन है।

235. (D) विधायी अधिनियमों और सामाजिक एवं शैक्षिक वातावरण द्वारा।
मौलिक कर्तव्यों को केवल अदालती आदेशों से लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये गैर-न्यायोचित हैं। इनके प्रभावी प्रवर्तन हेतु संसद विशिष्ट विधायी अधिनियम बना सकती है। हालांकि, इन कर्तव्यों के पालन का वास्तविक आधार नागरिकों की आंतरिक चेतना है। एक ऐसा शैक्षिक और सामाजिक वातावरण बनाना आवश्यक है जो नागरिकों को राष्ट्र के प्रति उनकी जिम्मेदारियों के बारे में जागरूक करे। यह नैतिक शिक्षा और नागरिक बोध के माध्यम से ही संभव है, जिससे मौलिक कर्तव्य समाज का स्वाभाविक आचरण और जीवन पद्धति बन सकें।

NODIA

236. (A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति न्यायपालिका को संविधान के रक्षक के रूप में कार्य करने की क्षमता देती है। सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती मामले में स्पष्ट किया था कि यह शक्ति 'मूल संरचना' का हिस्सा है। इसका अर्थ है कि संसद संशोधन शक्तियों का उपयोग कर न्यायालय से यह अधिकार नहीं छीन सकती कि वह कानूनों की संवैधानिकता की जांच करे। यह सिद्धांत कानून के शासन और शक्तियों के संतुलन को बनाए रखने हेतु बुनियादी महत्व रखता है। अतः कारण, अभिकथन हेतु एक सुदृढ़ विधिक और तर्कसंगत आधार प्रदान करता है।

237. (C) ब्रिटेन
'छाया मंत्रिमंडल' ब्रिटिश संसदीय प्रणाली की एक प्रभावी विशेषता है। इसमें मुख्य विपक्षी दल अपने वरिष्ठ सदस्यों का समूह बनाता है जो सत्तारूढ़ मंत्रिमंडल के समकक्ष होता है। प्रत्येक 'छाया मंत्री' सरकार के एक विशिष्ट विभाग की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखता है और संसद में वैकल्पिक नीतियां प्रस्तावित करता है। इसका मुख्य उद्देश्य सरकार को अधिक जवाबदेह बनाना और विपक्ष को भविष्य में शासन संभालने हेतु तैयार रखना है। यह प्रणाली सुनिश्चित करती है कि देश के पास हमेशा एक अनुभवी वैकल्पिक नेतृत्व उपलब्ध रहे, जो लोकतांत्रिक परिपक्वता का सूचक है।

238. (D) वित्त आयोग
वित्त आयोग एक महत्वपूर्ण संवैधानिक निकाय है जिसका गठन अनुच्छेद 280 के तहत प्रत्येक पाँच वर्ष में होता है। इसका प्राथमिक कार्य केंद्र और राज्यों के बीच करों के वितरण के सिद्धांतों पर अपनी सिफारिशें देना है। इसके अलावा यह राज्यों को दिए जाने वाले सहायता अनुदान हेतु भी मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित करता है। वित्त आयोग की सिफारिशें संघीय वित्तीय संतुलन बनाए रखने और राज्यों की जरूरतों को निष्पक्ष रूप से संबोधित करने हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। यह सहकारी संघवाद के आर्थिक आधार को मजबूत करने में केंद्रीय भूमिका निभाता है।

256. (C) केंद्र-राज्य संबंध
न्यायमूर्ति मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में 'पुंछी आयोग' का गठन 2007 में केंद्र-राज्य संबंधों की वर्तमान स्थिति की समीक्षा हेतु किया गया था। आयोग ने तेजी से बदलते परिदृश्य में संघवाद को मजबूत करने हेतु व्यापक सिफारिशें दीं। इसने राज्यपाल की भूमिका, अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग और राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर ध्यान केंद्रित किया। आयोग की रिपोर्ट केंद्र और राज्यों के बीच अधिक सहयोगपूर्ण और संतुलित संबंधों के निर्माण हेतु मार्गदर्शक है, जो राष्ट्र की एकता और विकासात्मक प्रगति हेतु अनिवार्य है।

257. (B) कोई भी सार्वजनिक हित से प्रेरित नागरिक या सामाजिक संगठन।
जनहित याचिका (पी.आई.एल.) की सबसे बड़ी विशेषता इसकी व्यापक पहुँच है। पारंपरिक मुकदमों के विपरीत, जहाँ केवल पीड़ित व्यक्ति ही न्यायालय जा सकता था, पी.आई.एल. में समाज का कोई भी जागरूक व्यक्ति जनहित के मुद्दे पर न्यायालय की शरण ले सकता है। यह उन मामलों में महत्वपूर्ण है जहाँ पीड़ित स्वयं बहुत गरीब या असहाय हैं। न्यायालय केवल एक पत्र के आधार पर भी संज्ञान ले सकता है। इसने भारतीय न्यायपालिका को सामाजिक परिवर्तन के एक सक्रिय और संवेदनशील माध्यम के रूप में बदल दिया है, जिससे न्याय सुलभ हुआ है।

258. (A) यह राष्ट्रीय जीवन के कई पहलुओं को सम्मिलित करने वाला एक व्यापक कार्यक्रम रखता है।
राजनीतिक दल और दबाव समूह दोनों राजनीति को प्रभावित करते हैं, परंतु उनके लक्ष्यों में अंतर होता है। राजनीतिक दलों का उद्देश्य सरकार बनाना होता है, इसलिए उनका कार्यक्रम देश के विकास, विदेश नीति और सुरक्षा जैसे व्यापक राष्ट्रीय मुद्दों को कवर करता है। इसके विपरीत, दबाव समूह आमतौर पर केवल अपने सदस्यों के विशिष्ट हितों या किसी एक विशेष मुद्दे तक ही सीमित रहते हैं। राजनीतिक दल पूरे राष्ट्र के प्रति उत्तरदायी होते हैं और चुनावी जनादेश प्राप्त करते हैं, जबकि दबाव समूह एक संकीर्ण और विशिष्ट समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं।

259. (C) किसी विशेष राजनीतिक दल के प्रति उनका दीर्घकालिक मनोवैज्ञानिक जुड़ाव।
चुनावी व्यवहार का 'दलीय पहचान' प्रतिरूप बताता है कि कई मतदाता किसी दल के साथ एक गहरा और स्थिर मनोवैज्ञानिक लगाव महसूस करते हैं। यह जुड़ाव अक्सर परिवार, सामाजिक परिवेश या प्रारंभिक अनुभवों के कारण विकसित होता है। ऐसे मतदाता प्रत्येक चुनाव में मुद्दों का विश्लेषण करने के बजाय अपनी दलीय निष्ठा के आधार पर ही वोट देते हैं। यह पहचान समय के साथ बहुत कम बदलती है और राजनीतिक दलों हेतु एक स्थायी 'वोट बैंक' का आधार बनती है, जो लोकतांत्रिक राजनीति में दलीय स्थिरता और संगठनात्मक मजबूती का मुख्य कारक है।

260. (D) पहचान, आत्म-सम्मान और राजनीतिक सत्ता में भागीदारी के लिए संघर्ष।
दलित दावे की राजनीति सदियों पुरानी सामाजिक दासता और अपमान के विरुद्ध एक व्यापक सांस्कृतिक और राजनीतिक विद्रोह है। इस राजनीति का केंद्र बिंदु अपनी मानवीय गरिमा को पुनः प्राप्त करना और व्यवस्था में अपना अधिकार मांगना है। यह केवल आर्थिक लाभों हेतु नहीं, बल्कि निर्णय लेने वाली संस्थाओं में सक्रिय और प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु है। इसने भारतीय लोकतंत्र के पारंपरिक ढांचे को चुनौती दी है, जिससे समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े लोगों में एक नई शक्ति और मुखर चेतना का संचार हुआ है, जो सामाजिक न्याय हेतु आवश्यक है।

261. (C) रियासतों ने संघ में सम्मिलित होने से इनकार कर दिया।
भारत सरकार अधिनियम 1935 ने एक 'अखिल भारतीय संघ' की परिकल्पना की थी जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों के साथ रियासतों का शामिल होना अनिवार्य था। हालांकि, इसके लिए यह शर्त थी कि कम से कम आधी रियासतें स्वेच्छा से इसमें शामिल होने हेतु सहमत हों। रियासतें अपनी स्वायत्तता खोने के डर से इस प्रस्ताव के प्रति उदासीन रहीं। परिणामस्वरूप, इस अधिनियम का संघीय हिस्सा कभी लागू नहीं हो सका और भारत केवल स्वतंत्रता के बाद ही एक वास्तविक संघ बन पाया। यह विफलता रियासतों और ब्रिटिश सत्ता के बीच जटिल संबंधों का परिणाम थी।

262. (D) वे संविधान के प्रारंभ होने पर स्वतः ही लागू हो जाते हैं।
नीति निदेशक तत्वों (डी.पी.एस.पी.) की एक प्रमुख विशेषता यह है कि ये स्वतः लागू नहीं होते। मौलिक अधिकारों के विपरीत, जिन्हें संविधान लागू होते ही विधिक संरक्षण प्राप्त हो गया, निदेशक तत्वों को प्रभावी बनाने हेतु राज्य को विशिष्ट कानून या नीतियां बनानी पड़ती हैं। उदाहरण हेतु, पंचायती राज को लागू करने हेतु विधायी अधिनियमों की आवश्यकता थी। इनका कार्यान्वयन राज्य की आर्थिक क्षमता और संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। ये तत्व भविष्य के सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु शासन को दिए गए निरंतर और महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश हैं।

263. (C) राष्ट्रपति की सिफारिश पर संसद के किसी भी सदन में।
संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत, नए राज्यों के निर्माण या सीमाओं में परिवर्तन से संबंधित विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। हालांकि, इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश अनिवार्य है। राष्ट्रपति ऐसा विधेयक पेश करने से पूर्व उसे संबंधित राज्य के विधानमंडल को उनके विचार जानने हेतु भेजते हैं। यह प्रक्रिया संघीय ढांचे के भीतर केंद्र की सर्वोच्च शक्ति को प्रदर्शित करती है, क्योंकि संसद राज्य की सहमति के बिना भी परिवर्तन करने का अधिकार रखती है, बशर्ते विधिक और संवैधानिक प्रक्रिया का पूर्णतः पालन किया गया हो।

Click Here to Buy book on Amazon

शक्तियां पंजाब जैसे राज्यों को देने की वकालत की गई थी। यह प्रस्ताव संघीय ढांचे के भीतर राज्यों हेतु अधिक वित्तीय और प्रशासनिक स्वायत्तता की तीव्र आकांक्षा का प्रतीक था। यद्यपि इसकी व्याख्याएं विवादित रहीं, परंतु यह भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय स्वायत्तता और संघवाद की बहस का एक मुख्य केंद्र बना रहा।

248. (A) चतुर्थ स्तंभ
लोकतंत्र में शासन के तीन अंगों के अतिरिक्त मीडिया को अक्सर 'चतुर्थ स्तंभ' कहा जाता है। यह इन अंगों की गतिविधियों पर निगरानी रखने और उन्हें जनता के प्रति जवाबदेह बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक स्वतंत्र मीडिया भ्रष्टाचार को उजागर करता है, जनहित के मुद्दों को उठाता है और नागरिकों को सूचित निर्णय लेने हेतु आवश्यक जानकारी प्रदान करता है। मीडिया की यह प्रहरी की भूमिका लोकतांत्रिक व्यवस्था के स्वास्थ्य और पारदर्शिता को बनाए रखने हेतु अपरिहार्य है। यह जनता की आवाज़ को शासन तक पहुँचाने का सशक्त और प्रभावी माध्यम है।

249. (C) औद्योगिक हड़ताल आंदोलन
किसान आंदोलनों का प्राथमिक सरोकार कृषि संबंधी मुद्दों जैसे भूमि अधिकार और लगान में कमी से होता है। औद्योगिक हड़ताल आंदोलन मुख्य रूप से कारखानों के श्रमिकों और उनके ट्रेड यूनियनों से संबंधित होते हैं, जिनका उद्देश्य वेतन वृद्धि और बेहतर कार्य परिस्थितियां प्राप्त करना होता है। हालांकि किसान और श्रमिक दोनों शोषण के विरुद्ध संघर्ष करते हैं, परंतु उनके कार्यक्षेत्र और तात्कालिक मांगें अलग-अलग होती हैं। किसान आंदोलन अक्सर ग्रामीण सामाजिक संरचना को प्रभावित करते हैं और भूमि सुधारों के माध्यम से सामाजिक न्याय की मांग को स्वर प्रदान करते हैं।

250. (A) मतदाताओं की समूह सदस्यता जैसे वर्ग, जाति और धर्म।
चुनावी व्यवहार का समाजशास्त्रीय प्रतिरूप इस विचार पर आधारित है कि मतदान का निर्णय व्यक्तिगत पसंद के बजाय सामाजिक पहचान से प्रभावित होता है। इसके अनुसार, मतदाता जिस सामाजिक समूह, जाति या धर्म का हिस्सा होता है, वह उसके राजनीतिक दृष्टिकोण को आकार देता है। मतदाता अक्सर अपने समूह के सामूहिक हितों और वफादारी के आधार पर वोट देते हैं। यह मॉडल बताता है कि चुनाव परिणामों की भविष्यवाणी हेतु समाज की जनसांख्यिकीय संरचना को समझना क्यों आवश्यक है। यह भारतीय राजनीति की जटिल वास्तविकता को समझने में सहायक है।

251. (D) अद्वितीय जातीय पहचान के आधार पर उग्रवाद और पृथकता की मांग।
उत्तर-पूर्व क्षेत्र में राष्ट्रीय एकीकरण हेतु सबसे बड़ी चुनौती वहां की विविध जातीय पहचानों से उत्पन्न असंतोष रहा है। कई समूहों ने अपनी विशिष्ट संस्कृति की रक्षा हेतु उग्रवाद का मार्ग अपनाया और भारतीय संघ से अलग होने की मांग की। केंद्र सरकार ने इसके समाधान हेतु शांति वार्ता, छठी अनुसूची के तहत विशेष सुरक्षा और विकास परियोजनाओं का सहारा लिया है। यह समस्या दर्शाती है कि राष्ट्रीय अखंडता बनाए रखने हेतु क्षेत्रीय आकांक्षाओं और जातीय गौरव का सम्मान करना तथा उन्हें मुख्यधारा में शामिल करना अत्यंत आवश्यक और अनिवार्य है।

252. (B) जाति, पंथ, लिंग या धर्म के आधार पर सभी भेदभाव समाप्त कर दिए जाएं।
भारतीय संविधान में निहित 'सामाजिक न्याय' की अवधारणा भेदभाव रहित जीवन सुनिश्चित करने का एक व्यापक दर्शन है। इसका मुख्य लक्ष्य समाज के उन ऐतिहासिक अन्यायों को दूर करना है जो जाति या धर्म जैसी पहचानों के कारण उत्पन्न हुए थे। यह वंचित वर्गों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों के उत्थान हेतु विशेष प्रावधान करने की अनुमति देता है ताकि वे समाज की मुख्यधारा में बराबरी से शामिल हो सकें। यह एक ऐसा समावेशी समाज बनाने का प्रयास है जहाँ अवसर प्रत्येक नागरिक हेतु समान हों और व्यक्तिगत गरिमा को सर्वोच्च प्राथमिकता प्राप्त हो।

253. (C) संयुक्त राज्य अमेरिका
"विधि की उचित प्रक्रिया" का सिद्धांत अमेरिकी संविधान की प्रमुख विशेषता है। यह सुनिश्चित करता है कि राज्य न केवल कानूनी प्रक्रिया का पालन करे, बल्कि वह कानून स्वयं भी न्यायपूर्ण और निष्पक्ष होना चाहिए। भारत ने प्रारंभ में ब्रिटिश अवधारणा "विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया" को अपनाया था, परंतु मेनका गांधी मामले के बाद भारतीय न्यायपालिका ने अमेरिकी अवधारणा के तत्वों को भी इसमें समाहित कर लिया है। अब भारत में भी किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता छीनने वाला कानून केवल प्रक्रियात्मक नहीं, बल्कि मूल रूप से भी तर्कसंगत होना अनिवार्य है।

254. (D) न्यायिक पुनरावलोकन
संवैधानिक संशोधनों की वैधता की जांच करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय के 'न्यायिक पुनरावलोकन' के अधिकार के अंतर्गत आती है। यद्यपि संसद को संशोधन की शक्ति प्राप्त है, परंतु न्यायपालिका यह सुनिश्चित करती है कि ये संशोधन 'मूल संरचना' का उल्लंघन न करें। यदि कोई संशोधन बुनियादी लोकतांत्रिक मूल्यों या मौलिक अधिकारों को क्षति पहुँचाता है, तो न्यायालय उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। यह शक्ति न्यायपालिका को संविधान के अंतिम रक्षक के रूप में स्थापित करती है और शासन के अंगों के बीच शक्तियों के संतुलन को बनाए रखती है।

255. (A) लोकसभा में
संविधान के अनुच्छेद 109 के अनुसार, धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है; इसे राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता। यह व्यवस्था 'कर के बिना प्रतिनिधित्व नहीं' के सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि लोकसभा सीधे जनता द्वारा निर्वाचित सदन है। धन विधेयक पर राज्यसभा की शक्तियां सीमित होती हैं; वह इसे केवल 14 दिनों तक रोक सकती है और सुझाव दे सकती है। यह वित्त के मामलों में जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों के वर्चस्व को सुनिश्चित करता है, जिससे राजकोषीय मामलों में लोकतांत्रिक नियंत्रण और जवाबदेही बनी रहती है।

NODIA

239. (A) विधायिका या कार्यपालिका की शक्तियों का अतिक्रमण करती हुई प्रतीत होती है।
'न्यायिक अतिरेक' एक आलोचनात्मक शब्द है जिसका उपयोग तब होता है जब न्यायपालिका कानून की व्याख्या से आगे बढ़कर नीति निर्माण या प्रशासनिक निर्णय लेने लगती है। यह तब होता है जब न्यायालय ऐसे आदेश जारी करता है जो सामान्यतः सरकार के कार्यकारी अंगों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। आलोचकों का मानना है कि इससे शक्तियों के पृथक्करण का संतुलन बिगड़ता है। हालांकि न्यायपालिका इसे तब उचित ठहराती है जब प्रशासन अपने कर्तव्यों को निभाने में विफल रहता है। यह न्यायिक सक्रियता और संवैधानिक मर्यादा के बीच के संतुलन का प्रश्न है।

240. (B) 1989
1989 के आम चुनाव भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण मोड़ थे, जिन्होंने एक-दलीय प्रभुत्व के युग को समाप्त कर दिया। इसके बाद गठबंधन की राजनीति का दौर शुरू हुआ, जहाँ राष्ट्रीय दलों को क्षेत्रीय दलों के समर्थन पर निर्भर रहना पड़ा। इस बदलाव ने भारतीय लोकतंत्र को अधिक बहुलवादी और संघीय बनाया, क्योंकि क्षेत्रीय आकांक्षाओं को राष्ट्रीय राजनीति में अधिक वजन मिलने लगा। यह संक्रमण दर्शाता है कि कैसे भारतीय मतदाताओं ने विविध राजनीतिक विकल्पों को अपनाकर सत्ता के केंद्रीकरण को संतुलित किया और शासन में भागीदारी को व्यापक बनाया।

241. (A) मतदाताओं को सभी उम्मीदवारों को अस्वीकार करने की अनुमति देना।
ई.वी.एम. में 'नोटा' विकल्प की शुरुआत 2013 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद हुई थी। यह मतदाताओं को यह अधिकार देता है कि यदि उन्हें कोई भी उम्मीदवार उपयुक्त नहीं लगता, तो वे अपनी नापसंदगी दर्ज करा सकें। नोटा का उद्देश्य राजनीतिक दलों को बेहतर और स्वच्छ छवि वाले उम्मीदवारों को उतारने हेतु विवश करना है। यह मतदाताओं की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा है और चुनावी प्रक्रिया की शुचिता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, जिससे जनता का लोकतांत्रिक विश्वास मजबूत होता है और उम्मीदवारों की गुणवत्ता में सुधार आता है।

242. (A) लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में।
महिला आरक्षण विधेयक, जिसे 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' कहा जाता है, का उद्देश्य विधायी संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना है। यह विधेयक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं हेतु कुल सीटों का एक-तिहाई भाग आरक्षित करने का प्रस्ताव करता है। पंचायतों में पहले से ही आरक्षण लागू है, परंतु राष्ट्रीय स्तर पर इसे लागू करना लैंगिक समानता की दिशा में ऐतिहासिक सुधार है। यह नीति निर्माण में महिलाओं के दृष्टिकोण को सशक्त रूप से शामिल करने का मार्ग प्रशस्त करेगा, जिससे देश का सर्वांगीण और समावेशी विकास सुनिश्चित हो सकेगा।

243. (C) प्रस्तावना
जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1946 में प्रस्तुत 'उद्देश्य प्रस्ताव' ने संविधान सभा के लक्ष्यों और आदर्शों को व्यक्त किया था। यही प्रस्ताव, परिष्कृत भाषा के साथ, भारतीय संविधान की 'प्रस्तवाना' के रूप में अपनाया गया। इसमें निहित मूल्य जैसे संप्रभुता, न्याय, स्वतंत्रता और समानता आज भी हमारे संविधान की आत्मा बने हुए हैं। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी माना जाता है क्योंकि यह पूरे दस्तावेज़ के पीछे के मूल दर्शन और राष्ट्र के भविष्य के प्रति निर्माताओं के संकल्प को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करती है। यह संविधान के महान उद्देश्यों की संक्षिप्त घोषणा है।

244. (D) शोषण के विरुद्ध अधिकार
अनुच्छेद 23 के तहत 'मानव तस्करी और बलात् श्रम का प्रतिषेध' एक मौलिक अधिकार है। यह प्रावधान समाज के कमजोर वर्गों को शारीरिक और आर्थिक शोषण से बचाने हेतु बनाया गया है। यह किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य करने हेतु मजबूर करने को कड़ाई से प्रतिबंधित करता है। यह अधिकार नागरिकों और गैर-नागरिकों दोनों को प्राप्त है और राज्य के साथ-साथ निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी सुरक्षा प्रदान करता है। यह सामाजिक न्याय और मानवीय गरिमा को सुनिश्चित करने की दिशा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण संवैधानिक सुरक्षा कवच है।

245. (A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
1976 का 42वां संशोधन अधिनियम इसके व्यापक परिवर्तनों के कारण 'लघु-संविधान' कहलाता है। इसके जवाब में, 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम को जनता पार्टी सरकार द्वारा लाया गया था ताकि आपातकाल के दौरान संवैधानिक मर्यादाओं के साथ की गई छेड़छाड़ को सुधारा जा सके। 44वें संशोधन ने नागरिक स्वतंत्रताओं को बहाल किया और यह सुनिश्चित किया कि भविष्य में आपातकाल जैसी शक्तियों का दुरुपयोग करना आसान न हो। ये दोनों संशोधन भारतीय संवैधानिक इतिहास की अत्यंत महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, जिन्होंने शासन के स्वरूप को परिभाषित करने में भूमिका निभाई।

246. (B) 12
संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार, राष्ट्रपति को राज्यसभा हेतु 12 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति प्राप्त है। ये सदस्य साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्रों में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्ति होते हैं। इस प्रावधान का मुख्य उद्देश्य देश की विशिष्ट प्रतिभाओं को बिना चुनावी प्रक्रिया के संसद में स्थान देना है ताकि उनके अनुभव से विधायी कार्यों को लाभ मिल सके। यह राज्यसभा के चरित्र को अधिक विद्वतापूर्ण और विविध बनाता है, जो राष्ट्रीय हित में महत्वपूर्ण चर्चाओं को समृद्ध करने में सहायक होता है।

247. (D) पंजाब के लिए अधिक राज्य स्वायत्तता।
1973 का आनंदपुर साहिब प्रस्ताव शिरोमणि अकाली दल द्वारा अपनाया गया एक महत्वपूर्ण राजनीतिक दस्तावेज था। इस प्रस्ताव में केंद्र-राज्य संबंधों के पुनर्गठन की मांग की गई थी, जिसमें केंद्र की शक्तियों को सीमित करने और शेष सभी

Downloaded from www.pdf.tube

264. (A) विधायिका और कार्यपालिका के बीच सद्भाव और सहयोग।
भारतीय संसदीय प्रणाली की सबसे बड़ी खूबी कार्यपालिका और विधायिका के बीच घनिष्ठ समन्वय है। चूँकि मंत्रिपरिषद के सदस्य संसद से ही चुने जाते हैं, इसलिए वे विधायी प्रक्रियाओं में सीधे शामिल होते हैं। यह व्यवस्था सरकार को अपने कानूनों को संसद में सुगमता से पारित कराने में सहायता करती है और शासन में गतिरोध की संभावना को कम करती है। कार्यपालिका अपने प्रत्येक कार्य हेतु विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है, जो उत्तरदायी शासन सुनिश्चित करता है। यह शक्तियों के संलयन पर आधारित एक सफल और स्थिर लोकतांत्रिक मॉडल है।

265. (C) राष्ट्रपति और केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में।
राज्य के राज्यपाल की भूमिका दोहरी और अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। वह एक ओर राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, वहीं दूसरी ओर वह केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वह उनके प्रसादपर्यंत पद धारण करता है। वह केंद्र और राज्य के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी का कार्य करता है, जो राज्य के शासन की रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजता है। यह पद भारतीय संघ की एकता सुनिश्चित करने और राज्य प्रशासन में संवैधानिक मर्यादाओं को बनाए रखने हेतु डिजाइन किया गया है।

266. (A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
न्यायिक सक्रियता ने अक्सर न्यायपालिका को शासन के उन क्षेत्रों में प्रवेश करने हेतु प्रेरित किया है जो परंपरागत रूप से कार्यपालिका के लिए आरक्षित थे। जब न्यायालय पर्यावरण या जेल सुधार पर विस्तृत निर्देश जारी करता है, तो यह शक्तियों के पृथक्करण की स्पष्ट रेखा को धुंधला कर देता है। आलोचकों के अनुसार, न्यायपालिका कभी-कभी प्रशासन चलाने लगती है। हालांकि, यह हस्तक्षेप अक्सर तब होता है जब अन्य अंग निष्क्रिय हो जाते हैं। अतः कारण, अभिकथन में उल्लिखित शक्तियों के संतुलन के असंतुलित होने की स्थिति की तर्कसंगत और सटीक व्याख्या करता है।

267. (D) चुनावी समूह
दबाव समूहों का वर्गीकरण उनकी प्रकृति के आधार पर किया जाता है। 'संस्थागत समूह', 'साहचर्य समूह' और 'गैर-साहचर्य समूह' दबाव समूहों के मान्य प्रकार हैं। 'चुनावी समूह' जैसा कोई विशिष्ट प्रकार दबाव समूहों के संदर्भ में नहीं होता, क्योंकि दबाव समूहों का मूल चरित्र ही यह है कि वे प्रत्यक्ष चुनावी राजनीति में भाग नहीं लेते। वे केवल बाहर से नीतियों को प्रभावित करते हैं। चुनाव लड़ना और सत्ता प्राप्त करना केवल राजनीतिक दलों का मुख्य कार्य है। अतः, दबाव समूहों के वैज्ञानिक अध्ययन में इस प्रकार की शब्दावली का उपयोग नहीं किया जाता।

268. (B) मतदाताओं के मतदान करने के तुरंत बाद उनके बीच।
'एग्जिट पोल' एक सर्वेक्षण है जो मतदान के दिन मतदान केंद्रों के बाहर किया जाता है। इसमें मतदाताओं से यह पूछा जाता है कि उन्होंने किसे वोट दिया है। इसका उद्देश्य मतगणना से पूर्व ही चुनाव परिणामों का एक विश्वसनीय और त्वरित अनुमान लगाना होता है। यद्यपि ये पोल आधिकारिक नहीं होते, परंतु वे मतदाताओं के रुझान को समझने में अत्यंत सहायक होते हैं। निर्वाचन आयोग ने चुनावी निष्पक्षता बनाए रखने हेतु मतदान के सभी चरणों के पूरा होने से पूर्व एग्जिट पोल के प्रसारण पर कानूनी प्रतिबंध लगा रखा है ताकि शेष मतदाता प्रभावित न हों।

269. (C) लिंग न्याय और समान नागरिक संहिता
1985 का शाह बानो मामला भारतीय राजनीति में एक ऐतिहासिक विवाद बन गया था। यह मामला एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला के गुजारा भत्ते की मांग से संबंधित था। सर्वोच्च न्यायालय ने शाह बानो के पक्ष में निर्णय दिया, जिसे कुछ संगठनों ने धार्मिक हस्तक्षेप माना। इसके बाद सरकार ने कानून बदलकर अदालती आदेश को निष्प्रभावी कर दिया। इस घटना ने पूरे देश में समान नागरिक संहिता और अल्पसंख्यक अधिकारों बनाम महिला अधिकारों पर एक तीव्र बहस छेड़ दी, जो आज भी भारतीय धर्मनिरपेक्षता और लिंग न्याय के संदर्भ में मुख्य विषय है।

270. (D) यह विश्वास कि एक धार्मिक समूह के हित अन्य समूहों के विरोधी हैं।
सांप्रदायिकता राष्ट्र-निर्माण हेतु एक गंभीर मानसिक और सामाजिक चुनौती है। यह इस दोषपूर्ण धारणा पर आधारित है कि एक धर्म के अनुयायियों के सामाजिक और राजनीतिक हित दूसरे धर्म के लोगों से अलग और विरोधी होते हैं। जब इस भावना का उपयोग राजनीतिक लाभ हेतु किया जाता है, तो यह समाज में घृणा और असुरक्षा का वातावरण पैदा करती है। यह साझा नागरिकता और राष्ट्रीय एकता के विचार को खंडित करती है। सांप्रदायिकता को रोकना केवल समुदायों के बीच संवाद, मूल्यपरक शिक्षा और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के प्रचार-प्रसार से ही संभव है।

271. (A) वह अपनी इच्छानुसार कोई भी संविधान बना सकती थी, जो बाहरी नियंत्रण से मुक्त हो।
संविधान सभा के 'संप्रभु' होने का तात्पर्य था कि उस पर किसी भी बाहरी शक्ति, जैसे ब्रिटिश संसद, का कोई नियंत्रण नहीं था। 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के बाद इसे पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त हो गई। यह सभा स्वतंत्र भारत हेतु सर्वोच्च नियम और कानून बनाने हेतु स्वतंत्र थी। इसने बिना किसी विदेशी हस्तक्षेप के भारतीय जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप एक अद्वितीय संविधान तैयार किया। यह संप्रभुता राष्ट्र की पूर्ण स्वतंत्रता और आत्म-निर्णय के अधिकार का सबसे शक्तिशाली प्रतीक थी, जिसने औपनिवेशिक विरासत को पूरी तरह समाप्त कर दिया।

272. (D) संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता।
भारतीय संवैधानिक व्यवस्था की एक अनूठी खूबी ब्रिटिश 'संसदीय संप्रभुता' और अमेरिकी 'न्यायिक सर्वोच्चता' के बीच का सामंजस्यपूर्ण संतुलन है। जहाँ संसद के पास कानून बनाने की व्यापक शक्ति है, वहीं न्यायपालिका यह सुनिश्चित करती है कि ये कानून संविधान की मूल मर्यादाओं और मौलिक

NODIA

राज्य के निर्माण हेतु सामाजिक और आर्थिक न्याय का मार्ग प्रशस्त करते हैं। ये दोनों भाग मिलकर संविधान के दर्शन और उसके द्वारा परिकल्पित आदर्श समाज की रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं। इनके बीच का संतुलन ही भारतीय लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति है, जो प्रत्येक व्यक्ति के विकास हेतु अनुकूल वातावरण निर्मित करता है।

223. (A) मौलिक अधिकार न्यायोचित हैं जबकि नीति निदेशक तत्व गैर-न्यायोचित हैं।
मौलिक अधिकारों और नीति निदेशक तत्वों के बीच बुनियादी अंतर उनकी विधिक प्रवर्तनीयता में है। मौलिक अधिकार 'न्यायोचित' हैं, अर्थात उल्लंघन होने पर नागरिक सीधे न्यायालय जाकर उन्हें लागू करवा सकता है। इसके विपरीत, नीति निदेशक तत्व 'गैर-न्यायोचित' हैं और इन्हें लागू करने हेतु राज्य को विवश नहीं किया जा सकता। हालांकि ये तत्व शासन में मौलिक हैं और राज्य का नैतिक कर्तव्य है कि वह नीतियों में इन्हें शामिल करे। यह अंतर नागरिक स्वतंत्रता और सामाजिक-आर्थिक विकास के लक्ष्यों के बीच के संबंध को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है।

224. (A) केवल I और II
संवैधानिक समीक्षा का उद्देश्य यह जांचना है कि प्रावधानों ने वांछित सामाजिक परिणामों को प्राप्त किया है या नहीं। वर्ष 2000 में न्यायमूर्ति वेंकटचलैया की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आयोग गठित किया गया था, जिसने शासन सुधार हेतु सिफारिशें दी थीं। यह विचार गलत है कि ऐसी समीक्षा केवल न्यायपालिका कर सकती है; कार्यपालिका भी विशेषज्ञों के आयोग गठित कर सकती है। ऐसी समीक्षाएं संविधान को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु सुझाव देने का स्वस्थ लोकतांत्रिक अभ्यास हैं, जो समय के साथ बदलती राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप सुधार का मार्ग खोलती हैं।

225. (B) कार्यपालिका की गतिविधियां पर जानकारी मांगकर उसे उत्तरदायी ठहराना।
संसद की बैठक का प्रथम घंटा 'प्रश्न काल' हेतु निर्धारित होता है, जो विधायी नियंत्रण का सशक्त साधन है। इस दौरान सांसद मंत्रियों से उनके विभागों के कामकाज और नीतियों के बारे में प्रश्न पूछते हैं। यह प्रक्रिया सरकार को अपनी कमियों को स्वीकार करने और सुधार करने हेतु विवश करती है। यह जनता की समस्याओं को सदन के सामने लाने और शासन की जवाबदेही सुनिश्चित करने का जीवंत माध्यम है। प्रश्न काल यह सुनिश्चित करता है कि कार्यपालिका अपनी शक्तियों का प्रयोग करते समय निरंतर सतर्क, पारदर्शी और जनता के प्रति उत्तरदायी बनी रहे।

226. (A) बार-बार होने वाले एकतरफा संशोधनों को रोकने और शक्तियों के विभाजन की रक्षा करने के लिए
संघीय व्यवस्था में लिखित और कठोर संविधान अनिवार्य है क्योंकि यह केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे की गारंटी देता है। यदि संविधान लचीला होता, तो केंद्र सरकार आसानी से अपनी शक्तियों का विस्तार कर राज्यों की स्वायत्तता समाप्त कर सकती थी। कठोर संशोधन प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि संघीय ढांचे में कोई महत्वपूर्ण बदलाव केवल व्यापक सहमति और राज्यों की भागीदारी से ही संभव हो। यह संवैधानिक स्थिरता प्रदान करता है और क्षेत्रीय पहचानों को राष्ट्रीय एकता के भीतर सुरक्षा एवं गरिमा की ठोस गारंटी प्रदान करता है।

227. (C) राज्यों को अधिक शक्तियां देने के लिए केंद्र-राज्य संबंधों का पुनर्गठन करना।
भारत के कई राज्यों में स्वायत्तता की मांग वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों के अधिक विकेंद्रीकरण पर केंद्रित रही है। राज्यों का तर्क है कि केंद्र पर अत्यधिक निर्भरता उनके स्थानीय शासन को प्रभावित करती है। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव जैसे दस्तावेजों ने भी अधिक राज्य स्वायत्तता की वकालत की थी। यह मांग अलगाववाद से भिन्न है, क्योंकि इसका उद्देश्य संविधान के संघीय ढांचे के भीतर ही राज्यों के अधिकारों को मजबूत करना है। यह सहकारी संघवाद के विचार को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और संवैधानिक प्रयास है।

228. (C) मामलों का भारी लंबित होना और न्याय में विलंब।
भारतीय न्यायिक प्रणाली की सबसे बड़ी चुनौती लाखों लंबित मामले हैं, जिससे न्याय में अत्यधिक देरी होती है। सुधारों का लक्ष्य अदालतों की कार्यक्षमता बढ़ाना और न्याय वितरण की गति तेज करना है। इसमें ई-कोर्ट मिशन के माध्यम से डिजिटलीकरण और रिक्त पदों पर समयबद्ध नियुक्तियां शामिल हैं। सुधारों का उद्देश्य आम नागरिक का न्यायपालिका पर विश्वास बनाए रखना है। समय पर न्याय मिलना एक मौलिक आवश्यकता है, जो स्वस्थ लोकतंत्र की स्थिरता और कानून के शासन की प्रभावशीलता हेतु अनिवार्य है। यह न्याय प्रक्रिया को अधिक सुलभ बनाता है।

229. (D) सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति करना।
दबाव समूह मांगों को मनवाने हेतु कई लोकतांत्रिक तरीके अपनाते हैं, जैसे पैरवी करना और मीडिया द्वारा जागरूकता फैलाना। वे शांतिपूर्ण विरोध और अदालतों में मुकदमेबाजी का भी सहारा लेते हैं। हालांकि, न्यायाधीशों की नियुक्ति करना उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है; यह एक संवैधानिक प्रक्रिया है जिसमें राष्ट्रपति और कॉलेजियम की भूमिका होती है। दबाव समूह केवल बाहर से नीतियों को प्रभावित कर सकते हैं, वे शासन की आंतरिक नियुक्तियों का सीधे संचालन नहीं कर सकते। यह शक्तियों के पृथक्करण और संवैधानिक मर्यादाओं के अनुरूप है।

230. (B) सभी वयस्कों को बिना किसी भेदभाव के मतदान करने का अधिकार है।
सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लोकतंत्र की आधारशिला है, जो अनुच्छेद 326 के तहत प्रत्येक नागरिक को 18 वर्ष की आयु पर मतदान का अधिकार देता है। इसमें जाति, धर्म, लिंग या संपत्ति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता। यह सिद्धांत इस विश्वास पर आधारित है कि प्रत्येक नागरिक के पास अपनी सरकार चुनने का समान अधिकार है। इसने समाज के कमजोर और हाशिए के वर्गों को राजनीतिक शक्ति प्रदान की

Click Here to Buy book on Amazon

281. (D) 26 जनवरी 1950
यद्यपि संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत कर लिया गया था, परंतु इसे पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इस विशेष तिथि का चयन ऐतिहासिक महत्व के कारण किया गया, क्योंकि 1930 में इसी दिन कांग्रेस ने 'पूर्ण स्वराज्य' की घोषणा की थी। संविधान के लागू होने के साथ ही भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया और ब्रिटिश राजतंत्र का औपचारिक संबंध समाप्त हो गया। इस दिन को हम प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, जो हमारे संवैधानिक शासन और राष्ट्र की नई एवं गरिमामय शुरुआत का प्रतीक है।

282. (A) राज्य के नीति निदेशक तत्व
अनुच्छेद 39(d) के तहत 'समान कार्य के लिए समान वेतन' का प्रावधान नीति निदेशक तत्वों का हिस्सा है। यह सिद्धांत सामाजिक और आर्थिक समानता प्राप्त करने के संवैधानिक लक्ष्य को दर्शाता है। इसका मुख्य उद्देश्य कार्यस्थल पर लिंग आधारित भेदभाव को समाप्त करना और यह सुनिश्चित करना है कि पुरुषों और महिलाओं दोनों को उनके श्रम का उचित प्रतिफल मिले। यद्यपि यह न्यायालयों द्वारा सीधे प्रवर्तनीय नहीं है, परंतु संसद ने विशिष्ट कानूनों के माध्यम से इस सिद्धांत को वैधानिक रूप प्रदान किया है, जो सामाजिक न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम है।

283. (C) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
भारत की संसद वास्तव में एक द्विसदनीय विधायिका है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा शामिल हैं। हालांकि, राष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता द्वारा नहीं किया जाता, बल्कि यह एक निर्वाचक मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इस निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित प्रतिनिधि शामिल होते हैं। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि राष्ट्रपति पूरे देश का प्रतिनिधित्व करें, लेकिन सरकार के संसदीय स्वरूप को बनाए रखते हुए वे सीधे जनता के प्रति नहीं बल्कि संवैधानिक रूप से निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के प्रति जवाबदेह हों।

284. (B) आंतरिक अशांति
प्रारंभ में, अनुच्छेद 352 में 'आंतरिक अशांति' को राष्ट्रीय आपातकाल का आधार माना गया था। हालांकि, 1975 के आपातकाल के दौरान इस शब्द के दुरुपयोग को देखते हुए, 1978 के 44वें संशोधन द्वारा इसे बदलकर 'सशस्त्र विद्रोह' कर दिया गया। अब केवल युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में ही राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। यह परिवर्तन आपातकालीन शक्तियों के मनमाने उपयोग को रोकने और नागरिक स्वतंत्रताओं की रक्षा करने हेतु किया गया था, जिससे देश के लोकतांत्रिक ढांचे को भविष्य के राजनीतिक खतरों से सुरक्षित किया जा सके।

285. (C) भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच।
सर्वोच्च न्यायालय का 'मूल क्षेत्राधिकार', जो अनुच्छेद 131 के तहत आता है, उन विवादों से संबंधित है जो सीधे सर्वोच्च न्यायालय में शुरू होते हैं। इसमें मुख्य रूप से संघीय ढांचे से जुड़े विवाद शामिल हैं, जैसे भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद, या दो या दो से अधिक राज्यों के बीच के विवाद। यह शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को संघीय संतुलन के अंतिम निर्णायक के रूप में स्थापित करती है। व्यक्तियों के बीच के सामान्य विवाद इस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आते। यह व्यवस्था संघ और इकाइयों के बीच विधिक समन्वय सुनिश्चित करती है।

286. (B) P-3, Q-4, R-1, S-2
ऐतिहासिक अदालती मामलों ने भारतीय कानून को नई दिशा प्रदान की है। एस.आर. बोम्मई मामले ने अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग पर अंकुश लगाया। विशाखा मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने हेतु व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए। मिनर्वा मिल्स मामले ने मौलिक अधिकारों और नीति निदेशक तत्वों के बीच संतुलन को संविधान का मूल ढांचा घोषित किया। डी.सी. वाधवा मामले में न्यायालय ने बार-बार अध्यादेश जारी करने की कार्यकारी शक्ति के दुरुपयोग के विरुद्ध निर्णय दिया, जो विधायी प्रक्रिया और लोकतांत्रिक मर्यादा को बनाए रखने हेतु आवश्यक था।

287. (A) हितों की अभिव्यक्ति और उनका समुच्चयन।
दबाव समूहों का प्राथमिक कार्य समाज के विभिन्न वर्गों के विशिष्ट हितों को एकत्रित करना और उन्हें शासन के समक्ष प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना है। वे एक 'मध्यस्थ' के रूप में कार्य करते हैं जो जनता की मांगों को नीति निर्माताओं तक पहुँचाते हैं। इससे सरकार को विभिन्न समूहों की चिंताओं को समझने में सहायता मिलती है। वे चुनाव नहीं लड़ते, बल्कि उनका पूरा ध्यान नीतिगत निर्णयों और कानूनों को अपने सदस्यों के अनुकूल प्रभावित करने पर होता है। यह प्रक्रिया लोकतंत्र में बहुलवाद को बढ़ावा देती है और निर्णय लेने को व्यापक बनाती है।

288. (D) एक स्वतंत्र परिसीमन आयोग।
लोकसभा और राज्य विधानसभाओं हेतु निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण (परिसीमन) एक स्वतंत्र 'परिसीमन आयोग' द्वारा किया जाता है। इस आयोग का गठन संसद द्वारा पारित अधिनियम के तहत होता है और इसमें सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश एवं निर्वाचन आयोग के सदस्य शामिल होते हैं। आयोग का मुख्य कार्य जनसंख्या के आधार पर क्षेत्रों का न्यायसंगत विभाजन करना है ताकि प्रत्येक क्षेत्र में लगभग समान संख्या में मतदाता हों। आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, जो इसकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता सुनिश्चित करता है।

289. (B) एक एकल केंद्रीय प्राधिकरण के तहत क्षेत्र को समेकित करना।
राष्ट्र-निर्माण के संदर्भ में 'राजनीतिक एकीकरण' वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बिखरी हुई रियासतों को एक साझा प्रशासनिक ढांचे के तहत लाया जाता है। भारत हेतु यह कार्य विशेष रूप से कठिन था क्योंकि स्वतंत्रता के समय देश सैकड़ों रियासतों में विभाजित था। सरदार पटेल के नेतृत्व में इन सभी को भारतीय संघ में शामिल कर एक एकीकृत संप्रभुता स्थापित

Downloaded from www.pdf.tube

63. 'प्रशासन' से 'विकास प्रशासन' की ओर ध्यान केंद्रित होना किसका संकेत है?
(A) दक्षता से प्रभावशीलता की ओर।
(B) केंद्रीकृत नियंत्रण से सहभागी प्रबंधन की ओर।
(C) विधि-व्यवस्था के कार्यों से सामाजिक-आर्थिक विकास कार्यों की ओर।
(D) प्रक्रियात्मक शुद्धता से लक्ष्य प्राप्ति की ओर।

64. निम्नलिखित में से कौन मुख्य कार्यपालिका का प्रकार नहीं है?
(A) एकल
(B) बहुल
(C) अध्यक्षीय
(D) न्यायिक

65. उच्चतम स्तर पर सरकारी गतिविधियों को व्यवस्थित करने का सबसे सामान्य और पारंपरिक रूप है:
(A) लोक निगम
(B) विभाग
(C) परिषद
(D) स्वतंत्र नियामक आयोग

66. "प्रशासन का विज्ञान राजनीति विज्ञान के उस अध्ययन का नवीनतम फल है जो लगभग बाईस सौ वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था।" यह कथन किसके प्रारंभिक प्रयासों को दर्शाता है?
(A) वुड्रो विल्सन
(B) ह्वाइट वाल्डो
(C) फ्रैंक मारिनी
(D) रॉबर्ट डाहल

67. किस संगठनात्मक सिद्धांत ने सबसे पहले उत्पादकता के लिए अनौपचारिक समूहों, मनोबल और संचार के महत्व पर बल दिया?
(A) वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत
(B) नौकरशाही सिद्धांत
(C) मानव संबंध सिद्धांत
(D) प्रशासनिक प्रबंधन सिद्धांत

68. यह विचार कि व्यवस्थित करने का कोई एक सर्वोत्तम विधि नहीं है और संगठनात्मक संरचना वातावरण और तकनीक जैसे कारकों पर 'आकस्मिक' (contingent) होनी चाहिए, किसका विषय है?
(A) आकस्मिकता सिद्धांत (Contingency Theory)
(B) व्यवस्था सिद्धांत (Systems Theory)
(C) शास्त्रीय सिद्धांत
(D) व्यवहारवादी सिद्धांत

69. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन I: केंद्रीकरण नीति की एकरूपता और नियंत्रण में सुगमता सुनिश्चित करता है।
कथन II: विकेंद्रीकरण से निर्णय लेने में विलंब हो सकता है और कर्मचारी मनोबल में कमी आ सकती है।
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
(D) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।

70. सूची I को सूची II के साथ सुमेलित कीजिए:
सूची I (विद्वान):
P. हेनरी फेयोल
Q. एफ.डब्ल्यू. टेलर
R. एल्टन मेयो
S. मैक्स वेबर।
सूची II (प्रमुख अवधारणा):
1. नौकरशाही
2. हाथोर्न प्रयोग
3. वैज्ञानिक प्रबंधन
4. प्रबंधन के सामान्य सिद्धांत।
(A) P-4, Q-3, R-2, S-1
(B) P-3, Q-4, R-1, S-2
(C) P-4, Q-2, R-3, S-1
(D) P-1, Q-3, R-2, S-4

71. किसी संगठन की संरचना उसके आकार, तकनीक और वातावरण द्वारा निर्धारित होती है। यह दृष्टिकोण किस सैद्धांतिक दृष्टिकोण का प्रतिनिधि है?
(A) निर्णय-निर्माण दृष्टिकोण
(B) आकस्मिकता (Contingency) दृष्टिकोण
(C) पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण
(D) मानव संबंध दृष्टिकोण

72. बढ़ते संगठन में 'स्टाफ' पदों के सृजन का प्राथमिक कारण क्या है?
(A) लाइन प्रबंधकों की संख्या कम करना।
(B) जटिलता और विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता को संभालना।
(C) असेंबली लाइन पर प्रत्यक्ष श्रमिकों का पर्यवेक्षण करना।
(D) संगठन में अधिक पदसोपानिक स्तर बनाना।

73. 'नियंत्रण के क्षेत्र' (span of control) की अवधारणा किस समस्या से निकटता से जुड़ी है?
(A) वित्तीय प्रबंधन
(B) पर्यवेक्षण और समन्वय
(C) बाहरी संबंध
(D) विधिक अनुपालन

74. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:
अभिकथन (A): व्यवस्था दृष्टिकोण (Systems Approach) एक संगठन को एक खुली व्यवस्था के रूप में देखता है।
कारण (R): यह स्वीकार करता है कि संगठन अपने वातावरण के साथ निरंतर अंतःक्रिया की स्थिति में है, जिससे वह इनपुट

NODIA

STUDYING FROM PDFs?

THINK AGAIN.

If you are studying only from PDFs,
you are wasting valuable time.

Research shows that learning from

PRINTED BOOKS has up to

4× HIGHER RETENTION

than studying from screens.

PRINT BOOK = BETTER MEMORY

PDF = LOWER RETENTION

Those who study from **PRINTED BOOKS**
move **AHEAD.**

Others are left **BEHIND**
in competition.

In competitive exams,
being average is not enough.

STAY ONE STEP AHEAD.

298. (A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
भारत का राष्ट्रपति राष्ट्र का औपचारिक प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक कार्यकारी शक्तियां प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं। अनुच्छेद 74 यह प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही करेंगे। यद्यपि सभी सरकारी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं, परंतु वे स्वतंत्र रुप से निर्णय नहीं ले सकते (कुछ विवेकाधीन शक्तियों को छोड़कर)। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि वास्तविक सत्ता जनता के प्रति उत्तरदायी निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथ में रहे। अतः कारण अभिकथन की पूर्णतः सही व्याख्या करता है।

299. (D) सत्तारूढ़ दल या उम्मीदवार के विरुद्ध हो।
'सत्ता विरोधी लहर' चुनावी व्यवहार का महत्वपूर्ण पहलू है, जो तब उत्पन्न होती है जब मतदाता वर्तमान सरकार के प्रदर्शन या भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों से असंतुष्ट होते हैं। इस स्थिति में, जनता परिवर्तन के पक्ष में मतदान करती है और सत्तारुढ़ दल को सत्ता से बाहर करने की प्रवृत्ति दिखाती है। यह लहर अक्सर किसी भी दलीय वफादारी से अधिक शक्तिशाली होती है और चुनावों में बड़े उलटफेर का कारण बनती है। यह लोकतंत्र में सरकार के प्रदर्शन के प्रति जनता की सामूहिक प्रतिक्रिया और जवाबदेही सुनिश्चित करने का एक सशक्त माध्यम है, जो निरंतर सुधार प्रेरित करता है।

300. (B) एक ऐसा समाज जहाँ सभी के साथ समान व्यवहार किया जाता है और सभी को समान अवसर प्राप्त होते हैं।
भारतीय संविधान का अंतिम लक्ष्य एक 'समतावादी समाज' की स्थापना है, जहाँ न्याय और समानता सर्वोपरि हो। इसका अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी जाति, धर्म या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। राज्य सभी नागरिकों को उनकी क्षमता के अनुसार विकसित होने हेतु समान अवसर और संसाधन उपलब्ध कराने हेतु प्रतिबद्ध है। यह परिकल्पना सामाजिक न्याय के उन सिद्धांतों पर टिकी है जो आर्थिक और सामाजिक असमानताओं को दूर करने का प्रयास करते हैं। ऐसा समाज ही लोकतंत्र को वास्तव में सार्थक, समावेशी और प्रत्येक नागरिक हेतु गरिमापूर्ण बना सकता है।

www.nodia.in

Click Here to Buy book on Amazon

(A) नियंत्रण का क्षेत्र
(B) आदेश की एकता
(C) पदसोपान (Hierarchy)
(D) लाइन और स्टाफ

20. विकास प्रशासन मुख्य रूप से किसके द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए उभरा?
(A) उत्तर-औद्योगिक समाज।
(B) विकसित पश्चिमी राष्ट्र।
(C) बहुराष्ट्रीय निगम।
(D) नए स्वतंत्र और विकासशील देश।

21. निम्नलिखित परिदृश्य को पढ़ें और उसके बाद आने वाले प्रश्न का उत्तर दें:
एक सरकारी एजेंसी को व्यावसायिक सिद्धांतों पर राष्ट्रीय रेलवे प्रणाली चलाने के विशिष्ट अधिदेश के साथ बनाया गया है, जिसका अपना बजट और भर्ती नीतियां हैं, लेकिन वह अंततः संसद के प्रति उत्तरदायी है। संगठन के इस रूप को सबसे बेहतर किस रूप में पहचाना जाता है:
(A) विभाग
(B) परिषद
(C) लोक निगम
(D) स्टाफ एजेंसी

22. निम्नलिखित को उनके वैचारिक विकास के कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें:
1. लोक प्रशासन में व्यवस्था दृष्टिकोण
2. मानव संबंध सिद्धांत
3. शास्त्रीय सिद्धांत (वैज्ञानिक प्रबंधन)
4. विकास प्रशासन
(A) 3, 2, 1, 4
(B) 1, 2, 3, 4
(C) 2, 3, 4, 1
(D) 3, 1, 2, 4

23. निर्णय लेने में 'तथ्य-मूल्य द्विभाजन' (fact-value dichotomy) किसका एक महत्वपूर्ण योगदान था?
(A) फ्रेड डब्ल्यू. रिग्स
(B) एल्टन मेयो
(C) हेनरी फेयोल
(D) हर्बर्ट ए. साइमन

24. निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है?
(A) चेस्टर बर्नार्ड - वैज्ञानिक प्रबंधन
(B) फ्रेड रिग्स - पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण
(C) हर्बर्ट साइमन - निर्णय-निर्माण दृष्टिकोण
(D) मैक्स वेबर - नौकरशाही सिद्धांत

25. एक 'स्टाफ' एजेंसी के कार्यों में सामान्यतः निम्नलिखित को छोड़कर सभी सम्मिलित होते हैं:
(A) लाइन अधिकारियों को परामर्श देना।
(B) अनुसंधान और योजना जैसी विशिष्ट सेवाएं प्रदान करना।
(C) परिचालन इकाइयों को प्रत्यक्ष आदेश जारी करना।
(D) नीतिगत विषयों पर मुख्य कार्यपालिका को परामर्श देना।

26. संगठन के सिद्धांत के रूप में 'केंद्रीकरण' का तात्पर्य है:
(A) संगठन के उच्च स्तरों पर निर्णय लेने के अधिकार का संकेंद्रण।
(B) एक ही स्थान पर कार्यालयों का भौगोलिक संकेंद्रण।
(C) कर्मचारियों के बीच कार्यों का विशेषीकरण।
(D) सभी संगठनात्मक योजनाओं का एक एकल मास्टर प्लान में एकीकरण।

27. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन I: हाथोर्न प्रयोग (Hawthorne Studies), जो प्रारंभ में उत्पादकता पर भौतिक स्थितियों के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए बनाए गए थे, अंततः सामाजिक कारकों के महत्व पर प्रकाश डालने लगे।
कथन II: हाथोर्न प्रभाव (Hawthorne effect) अध्ययन के प्रतिभागियों की अपने व्यवहार को परिवर्तित करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है क्योंकि उनका अवलोकन किया जा रहा है।
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
(D) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।

28. 'इनपुट-थ्रूपुट-आउटपुट-फीडबैक' तंत्र संगठनों के अध्ययन के किस दृष्टिकोण की एक केंद्रीय विशेषता है?
(A) पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण
(B) निर्णय-निर्माण दृष्टिकोण
(C) व्यवस्था दृष्टिकोण
(D) मानव संबंध दृष्टिकोण

29. एक विभाग और एक लोक निगम के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर यह है कि एक लोक निगम में सामान्यतः होता है:
(A) कम परिचालन स्वायत्तता।
(B) सभी कर्मचारियों के लिए सिविल सेवा नियमों का अधिक कठोरता से अनुपालन।
(C) अपने सभी व्यय के लिए वार्षिक सरकारी बजट से प्रत्यक्ष वित्तपोषण।
(D) अधिक वित्तीय लचीलापन।

30. मुख्य कार्यपालिका की भूमिकाओं के संदर्भ में, किस कार्य में औपचारिक कर्तव्य और राज्य के प्रतीकात्मक प्रमुख के रूप में कार्य करना सम्मिलित है?
(A) राजनीतिक कार्य
(B) राज्य के प्रमुख (Head of State) की भूमिका
(C) प्रशासनिक कार्य
(D) विधायी कार्य

NODIA

सूची I (संगठनात्मक रूप):
P. विभाग
Q. लोक निगम
R. परिषद
S. अनौपचारिक संगठन।
सूची II (प्राथमिक विशेषता):
1. सार्वजनिक उत्तरदायित्व के साथ व्यावसायिक सिद्धांत
2. सामूहिक निर्णय लेने या सलाहकार की भूमिका
3. सामाजिक संबंधों और मानदंडों पर आधारित
4. सरकार की पारंपरिक पदसोपानिक इकाई।
(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-4, Q-1, R-2, S-3
(C) P-4, Q-2, R-1, S-3
(D) P-3, Q-1, R-4, S-2

11. 'लाइन और स्टाफ' (Line और Staff) संगठन में मुख्य रूप से 'लाइन' एजेंसी का कार्य कौन सा है?
(A) मुख्य कार्यपालिका को विशेषज्ञ परामर्श प्रदान करना।
(B) अनुसंधान और डेटा विश्लेषण करना।
(C) अन्य इकाइयों के प्रदर्शन का लेखा-परीक्षण करना।
(D) संगठन के प्राथमिक उद्देश्यों को पूर्ण करना।

12. मुख्य कार्यपालिकाओं के संदर्भ में, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति किसका उदाहरण है?
(A) बहुल और संसदीय कार्यपालिका
(B) एकल और अध्यक्षीय कार्यपालिका
(C) एकल और संसदीय कार्यपालिका
(D) बहुल और अध्यक्षीय कार्यपालिका

13. संगठन के प्रति व्यवस्था दृष्टिकोण (Systems Approach) एक संगठन को इस रूप में देखता है:
(A) अपने वातावरण से स्वतंत्र एक बंद व्यवस्था।
(B) निश्चित नियमों द्वारा शासित विशुद्ध रूप से एक यांत्रिक संरचना।
(C) परस्पर संबंधित और परस्पर निर्भर भागों का एक समूह जो समग्र रूप से कार्य करता है।
(D) केवल आर्थिक प्रोत्साहन से प्रेरित व्यक्तियों का समूह।

14. हर्बर्ट साइमन की निर्णय-निर्माण की अवधारणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. निर्णय लेने वाले संज्ञानात्मक सीमाओं के कारण 'सीमित तर्कसंगतता' (bounded rationality) के साथ कार्य करते हैं।
2. 'संतोषप्रद' (satisficing) मॉडल बताता है कि निर्णय लेने वाले पहले संतोषजनक विकल्प को चुनते हैं, जो आवश्यक रूप से इष्टतम (optimal) नहीं होता है।
3. साइमन ने मूल्यों के स्थान पर निर्णय लेने में तथ्यों की भूमिका को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया था।
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1
(D) 1, 2 और 3

15. 'औपचारिक संगठन' की सबसे विशिष्ट विशेषता क्या है?
(A) औपचारिक अधिकार संरचना के साथ सचेत रूप से समन्वित गतिविधियों की एक प्रणाली।
(B) अनौपचारिक सामाजिक गुटों और व्यक्तिगत मित्रता की निरंतर उपस्थिति।
(C) संचार के प्रतिरूप जो मुख्य रूप से अनौपचारिक माध्यमों (grapevine) से प्रवाहित होते हैं।
(D) व्यक्तिगत स्वाभाविकता और व्यक्तिपरक भावनात्मक अभिव्यक्ति का उच्च स्तर।

16. पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण में 'प्रिज्मीय समाज' (Prismatic Society) की अवधारणा उस समाज का वर्णन करती है जो:
(A) अपनी संरचनाओं में अत्यधिक विकसित और विभेदित है।
(B) एक संक्रमणकालीन समाज है जो पारंपरिक और आधुनिक दोनों विशेषताओं को प्रदर्शित करता है।
(C) एक पारंपरिक समाज है जो अपने कार्यों में काफी हद तक अविभेदित रहता है।
(D) एक ऐसा समाज है जो सभी बाहरी प्रभावों से पूरी तरह पृथक रहता है।

17. 'मुख्य कार्यपालिका' (Chief Executive) के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
(A) मुख्य कार्यपालिका प्रशासन के लिए अंतिम उत्तरदायित्व रखती है।
(B) मुख्य कार्यपालिका के कार्य प्रकृति में विशुद्ध रूप से प्रशासनिक होते हैं।
(C) मुख्य कार्यपालिका नीति निर्धारण और विधायी नेतृत्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
(D) मुख्य कार्यपालिका की भूमिका में कई प्रणालियों में कमांडर-इन-चीफ के रूप में कार्य करना सम्मिलित है।

18. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:
अभिकथन (A): विकेंद्रीकरण में केंद्र सरकार से संगठन के निचले स्तरों या अधीनस्थ इकाइयों को अधिकार का हस्तांतरण सम्मिलित है।
कारण (R): विकेंद्रीकरण से निर्णय लेने में तीव्रता आ सकती है और स्थानीय आवश्यकताओं के प्रति अधिक संवेदनशीलता उत्पन्न हो सकती है।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

19. 'स्केलर चेन' (scalar chain) एक अवधारणा है जो संगठन के किस सिद्धांत के साथ सबसे निकटता से जुड़ी है?

Downloaded from www.pdf.tube

(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-4, Q-1, R-2, S-3
(C) P-4, Q-2, R-1, S-3
(D) P-3, Q-1, R-4, S-2

41. 'लाइन और स्टाफ' संगठन में मुख्य रूप से 'लाइन' एजेंसी का कार्य कौन सा है?
(A) मुख्य कार्यपालिका को विशेषज्ञ परामर्श प्रदान करना।
(B) अनुसंधान और डेटा विश्लेषण करना।
(C) अन्य इकाइयों के प्रदर्शन का लेखा-परीक्षण करना।
(D) संगठन के प्राथमिक उद्देश्यों को पूर्ण करना।

42. 'सीमित तर्कसंगतता' (bounded rationality) की अवधारणा किसकी धारणा को चुनौती देती है?
(A) राजनीतिक मानव (Political Man)
(B) आर्थिक मानव (Economic Man)
(C) सामाजिक मानव (Social Man)
(D) आत्म-सिद्ध मानव (Self-actualizing Man)

43. निम्नलिखित में से कौन बहुल मुख्य कार्यपालिका (plural chief executive) का उदाहरण है?
(A) संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति
(B) यूनाइटेड किंगडम का प्रधानमंत्री
(C) स्विट्जरलैंड की संघीय परिषद (Federal Council)
(D) जर्मनी का चांसलर

44. आधुनिक जटिल संगठनों में 'आदेश की एकता' के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना यह है कि:
(A) यह अनिवार्य रूप से कर्मचारियों के बीच पेशेवर अनुशासन की कमी की ओर ले जाता है।
(B) यह स्वाभाविक रूप से अक्षम है और निर्णय लेने की प्रक्रिया को काफी धीमा कर देता है।
(C) यह एक व्यक्ति के भीतर प्रशासनिक शक्ति को अत्यधिक केंद्रित करता है।
(D) कार्यात्मक विशेषीकरण और विशेषज्ञ अधिकार के कारण यह प्रायः अव्यावहारिक होता है।

45. यह अवधारणा कि प्रशासनिक तकनीकें व्यवसाय का एक क्षेत्र हैं जो राजनीति के उचित क्षेत्र से बाहर हैं, किसका एक केंद्रीय सिद्धांत है?
(A) राजनीति-प्रशासन द्विभाजन
(B) विकास प्रशासन
(C) व्यवस्था दृष्टिकोण
(D) पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण

46. निम्नलिखित में से कौन सा रिग्स के प्रिज्माटिक समाज की तीन विशेषताओं में से एक नहीं है?
(A) विषमता (Heterogeneity)
(B) सजातीयता (Homogeneity)
(C) औपचारिकतावाद (Formalism)
(D) अतिव्यापन (Overlapping)

47. 'सैटिस्फाइसिंग' (satisficing) शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था?
(A) चेस्टर बर्नार्ड
(B) फ्रेड रिग्स
(C) हर्बर्ट साइमन
(D) ड्वाइट वाल्डो

48. मानव संबंध सिद्धांत (Human Relations Theory) का एक प्रमुख योगदान किस पर इसका ध्यान केंद्रित करना था?
(A) संगठन की औपचारिक संरचना।
(B) श्रमिकों के आर्थिक उद्देश्य।
(C) प्रबंधन के सार्वभौमिक सिद्धांत।
(D) कर्मचारियों की सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं।

49. 'विकेंद्रीकरण' निर्णय लेने के अधिकार का प्रसार है:
(A) बाहरी परामर्श एजेंसियों को।
(B) संगठन के उच्चतम स्तर को।
(C) संगठनात्मक पदसोपान के भीतर निचले स्तरों को।
(D) एक एकल केंद्रीय योजना इकाई को।

NODIA

50. मुख्य कार्यपालिका के विधायी कार्य में सामान्यतः सम्मिलित होता है:
(A) न्यायाधीशों की नियुक्ति करना और क्षमादान देना।
(B) विधि की अनुशंसा करना, अध्यादेश जारी करना और वीटो शक्ति का उपयोग करना।
(C) सशस्त्र बलों की कमान संभालना।
(D) सरकारी विभागों के दैनिक कार्यों की देखरेख करना।

51. रिग्सियन मॉडल में 'औपचारिकतावाद' (formalism) क्या दर्शाता है?
(A) प्रशासनिक अभ्यास में औपचारिक नियमों और विनियमों के अनुपालन का उच्च स्तर।
(B) अनौपचारिक नेटवर्क की तुलना में औपचारिक संचार चैनलों के लिए निरंतर प्राथमिकता।
(C) प्रशासनिक प्रक्रियाओं और आवश्यकताओं की एक कठोर और जटिल प्रणाली।
(D) औपचारिक कानूनी निर्देशों और वास्तविक प्रशासनिक अभ्यास के बीच एक बड़ा अंतर।

52. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन I: नियंत्रण का विस्तृत क्षेत्र (wide span of control) कम पदसोपानिक स्तरों वाले 'सपाट' (flat) संगठन में परिणत होता है।
कथन II: नियंत्रण का संकीर्ण क्षेत्र (narrow span of control) कई पदसोपानिक स्तरों वाले 'लंबवत' (tall) संगठन में परिणत होता है।
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
(D) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।

31. राजनीति-प्रशासन द्विभाजन (politics-administration dichotomy), जो इस विषय के विकास में एक आधारभूत विषय रहा है, को 1887 के एक निबंध में किसके द्वारा प्रसिद्ध रूप से व्यक्त किया गया था?
(A) वुड्रो विल्सन
(B) फ्रैंक गुडनाऊ
(C) मैक्स वेबर
(D) एफ.डब्ल्यू. टेलर

32. फ्रेड रिग्स के प्रिज्माटिक-साला मॉडल (Prismatic-Sala model) के संदर्भ में 'विषमता' (heterogeneity) का क्या अर्थ है?
(A) उच्च सामाजिक गतिशीलता और संरचनात्मक समानता की विशेषता वाली स्थिति।
(B) आधुनिक मानदंडों और पारंपरिक सामाजिक मूल्यों की एक साथ उपस्थिति।
(C) एक एकल, एकसमान और सजातीय संस्कृति के प्रभुत्व वाला समाज।
(D) विशुद्ध रूप से पारंपरिक कृषि उत्पादन पर आधारित आर्थिक प्रणाली।

33. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:
अभिकथन (A): औपचारिक संगठनों के भीतर अनौपचारिक संगठन अनिवार्य रूप से उपस्थित होते हैं।
कारण (R): मनुष्य स्वाभाविक रूप से सामाजिक संबंध और समूह बनाते हैं जो आधिकारिक संगठनात्मक चार्ट द्वारा निर्धारित नहीं होते हैं।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

34. संगठन के एक रूप के रूप में 'परिषद' (Council) का उपयोग प्रायः किसके लिए किया जाता है?
(A) सरकार के मुख्य परिचालन कार्यों को निष्पादित करना।
(B) व्यावसायिक गतिविधियों के माध्यम से लाभ अर्जित करना।
(C) एक सामूहिक निकाय द्वारा विचार-विमर्श, परामर्श या विनियमन की आवश्यकता वाले कार्य।
(D) त्वरित अनुक्रिया के लिए आदेश की एक कठोर श्रृंखला बनाए रखना।

35. 'गैंगप्लैंक' (gangplank) या 'लेवल जंपिंग' के माध्यम से तीव्र संचार प्राप्त करने के लिए कभी-कभी किस संगठनात्मक सिद्धांत का उल्लंघन किया जाता है?
(A) आदेश की एकता
(B) पदसोपान (Hierarchy)
(C) नियंत्रण का क्षेत्र
(D) विकेंद्रीकरण

36. संगठन के शास्त्रीय सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. वे संगठन के भीतर अनौपचारिक सामाजिक संरचनाओं पर बल देते हैं।
2. वे संगठनों को मशीनों के रूप में और श्रमिकों को उस मशीन के पुर्जों के रूप में देखते हैं।
3. वे प्रबंधन के सार्वभौमिक सिद्धांतों का प्रस्ताव करते हैं जो सभी संगठनों पर लागू होते हैं।
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3

37. साइमन के ढांचे में "नियोजित निर्णय" (Programmed decisions) उन निर्णयों को संदर्भित करते हैं जो:
(A) नवीन, असंरचित और उच्च परिणामों वाले निर्णय होते हैं।
(B) केवल शीर्ष स्तर के कार्यकारी प्रबंधन द्वारा लिए जाते हैं।
(C) पूरी तरह से प्रबंधक के अंतर्ज्ञान और व्यक्तिगत निर्णय पर आधारित होते हैं।
(D) नियमित होते हैं और एक निश्चित, स्थापित प्रक्रिया का अनुकरण करते हैं।

38. विकास प्रशासन का प्राथमिक लक्ष्य है:
(A) सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन लाना।
(B) समाज में विधि-व्यवस्था बनाए रखना।
(C) राज्य के लिए राजस्व एकत्र करना।
(D) निजी क्षेत्र की गतिविधियों को विनियमित करना।

39. व्यवस्था दृष्टिकोण (Systems Approach) में, इनपुट को आउटपुट में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है?
(A) फीडबैक
(B) थ्रूपुट (Throughput)
(C) एन्ट्रॉपी
(D) वातावरण

40. सूची I को सूची II के साथ सुमेलित कीजिए:
सूची I (सिद्धांत):
P. नियंत्रण का क्षेत्र
Q. पदसोपान
R. आदेश की एकता
S. लाइन और स्टाफ।
सूची II (विवरण):
1. अधिकार ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होता है
2. एक कर्मचारी एक ही उच्चाधिकारी को रिपोर्ट करता है
3. आदेश और सलाहकार कार्यों का पृथक्करण
4. अधीनस्थों की वह संख्या जिसे एक वरिष्ठ संभाल सकता है।

Click Here to Buy book on Amazon

अध्याय 05
लोक प्रशासन एवं संगठन सिद्धांत

1. निम्नलिखित में से कौन लोक प्रशासन को एक विषय के रूप में सबसे अच्छी तरह परिभाषित करता है?
(A) राजनीतिक शक्ति और समाज में इसके वितरण का अध्ययन।
(B) लोक नीति का कार्यान्वयन और सरकारी गतिविधियों का प्रबंधन।
(C) विधायी निकाय द्वारा कानूनों का मसौदा तैयार करने और उन्हें अधिनियमित करने की प्रक्रिया।
(D) अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और कूटनीति का सैद्धांतिक विश्लेषण।

2. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन I: लोक प्रशासन में निर्णय-निर्माण दृष्टिकोण इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि लोक अधिकारी विकल्पों तक कैसे पहुँचते हैं।
कथन II: यह दृष्टिकोण तर्कसंगत-व्यापक मॉडल (rational-comprehensive model) को प्रशासनिक निर्णय लेने के एकमात्र वैध विवरण के रूप में मानता है।
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
(D) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।

3. 'प्रशासन की पारिस्थितिकी' (ecology of administration) की अवधारणा को व्यवस्थित रूप से किस विद्वान द्वारा विकसित किया गया था?
(A) हर्बर्ट ए. साइमन
(B) चेस्टर आई. बर्नार्ड
(C) फ्रेड डब्ल्यू. रिग्स
(D) वुड्रो विल्सन

4. लोक प्रशासन के अध्ययन का कौन सा दृष्टिकोण प्रशासनिक प्रणाली और उसके बाहरी वातावरण के बीच अंतःक्रिया पर बल देता है?
(A) व्यवहारवादी दृष्टिकोण
(B) संस्थागत दृष्टिकोण
(C) दार्शनिक दृष्टिकोण
(D) पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण

5. निम्नलिखित में से कौन सा विकास प्रशासन का लक्षण नहीं है?
(A) परिवर्तन-उन्मुख
(B) लक्ष्य-उन्मुख
(C) यथास्थिति-उन्मुख
(D) ग्राहक-उन्मुख

6. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:
अभिकथन (A): मैक्स वेबर के नौकरशाही के सिद्धांत को शास्त्रीय संगठन सिद्धांत का आधार माना जाता है।
कारण (R): वेबर का मॉडल पदसोपानिक संरचना और स्पष्ट रूप से परिभाषित नियमों के माध्यम से प्राप्त दक्षता, पूर्वानुमान और तर्कसंगतता पर बल देता है।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

7. किसी संगठन में 'आदेश की एकता' (Unity of CommऔR) के सिद्धांत का अर्थ है कि:
(A) सभी कर्मचारियों को एक साझा संगठनात्मक लक्ष्य की दिशा में कार्य करना चाहिए।
(B) संगठन के शीर्ष पर एक एकल, एकीकृत नेतृत्व संरचना होनी चाहिए।
(C) संगठन की सभी इकाइयों को एक ही योजना के अंतर्गत एकीकृत किया जाना चाहिए।
(D) एक कर्मचारी को केवल एक ही वरिष्ठ से आदेश प्राप्त होने चाहिए।

8. कौन सी अवधारणा उन अधीनस्थों की संख्या को संदर्भित करती है जिन्हें एक प्रबंधक प्रभावी ढंग से पर्यवेक्षित कर सकता है?
(A) नियंत्रण का क्षेत्र (Span of Control)
(B) पदसोपान (Hierarchy)
(C) निर्देशन की एकता
(D) केंद्रीकरण

9. स्वाभाविक सामाजिक संबंधों, समूह मानदंडों और अनौपचारिक संचार की विशेषता वाले संगठन को सबसे अच्छी तरह इस रूप में वर्णित किया जा सकता है:
(A) एक औपचारिक संगठन
(B) एक नौकरशाही संगठन
(C) एक अनौपचारिक संगठन
(D) एक लोक निगम

10. सूची I को सूची II के साथ सुमेलित कीजिए:

NODIA

53. संगठन के शास्त्रीय सिद्धांत की प्रायः किसके लिए आलोचना की जाती है?
(A) मानवीय भावनाओं और सामाजिक कारकों पर अत्यधिक बल देना।
(B) संरचना और दक्षता की आवश्यकता की उपेक्षा करना।
(C) संगठन को एक बंद व्यवस्था के रूप में मानना और मानवीय तत्व की उपेक्षा करना।
(D) बहुत लचीला होना और ठोस सिद्धांतों की कमी होना।

54. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:
अभिकथन (A): सरकार के व्यावसायिक या औद्योगिक उपक्रमों के प्रबंधन के लिए लोक निगमों का निर्माण किया जाता है।
कारण (R): संगठन के विभागीय रुप को कुशल व्यावसायिक संचालन के लिए बहुत कठोर और प्रक्रियात्मक रूप से बाधित माना जाता है।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

55. मुख्य कार्यपालिका की प्रशासनिक भूमिका को निम्नलिखित में से किस गतिविधि द्वारा सबसे अच्छी तरह से उदाहरण दिया गया है?
(A) किसी विदेशी राष्ट्र के साथ संधि पर हस्ताक्षर करना।
(B) 'स्टेट ऑफ द यूनियन' संबोधन देना।
(C) विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर वीटो करना।
(D) विभागों के प्रमुखों की नियुक्ति करना, उन्हें निर्देशित करना और पदमुक्त करना।

56. व्यवस्था दृष्टिकोण (Systems Approach) का मुख्य तर्क यह है कि किसी संगठन का अस्तित्व और प्रभावशीलता उसकी किस क्षमता पर निर्भर करती है?
(A) एक कठोर और अपरिवर्तनीय आंतरिक संरचना बनाए रखना।
(B) अपने परिवर्तनशील बाहरी वातावरण के अनुकूल होना।
(C) प्रत्येक स्थिति में अल्पकालिक लाभ को अधिकतम करना।
(D) अपने कर्मचारियों पर कठोर अनुशासन और नियंत्रण लागू करना।

57. शास्त्रीय विचारधारा से जुड़े 'संगठन के सिद्धांतों' के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. श्रम विभाजन
2. आदेश की एकता
3. सीमित तर्कसंगतता
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 3
(D) 1, 2 और 3

NODIA

58. हर्बर्ट साइमन के अनुसार, 'अनियोजित निर्णयों' (non-programmed decisions) की आवश्यकता उन स्थितियों के लिए होती है जो:
(A) पुनरावृत्ति वाली और नियमित होती हैं।
(B) अच्छी तरह से संरचित और पूर्वानुमानित होती हैं।
(C) निचले स्तर के कर्मचारियों द्वारा संभाली जाती हैं।
(D) नवीन, असंरचित और जटिल होती हैं।

59. निम्नलिखित में से कौन 'पदसोपान' (hierarchy) के सिद्धांत को सबसे अच्छी तरह दर्शाता है?
(A) जनरल से लेकर सिपाही तक एक सेना की कमान संरचना।
(B) एक परियोजना पर सहयोग करने वाले विभिन्न क्षेत्रों के वैज्ञानिकों का एक दल।
(C) एक प्रणाली जहाँ प्रत्येक कर्मचारी सीधे मुख्य कार्यपालक अधिकारी (CEO) से संवाद कर सकता है।
(D) कार्य के लचीले घंटों की अनुमति देने वाली कंपनी की नीति।

60. संगठन के 'परिषद' (Council) रूप, जैसे कि नगर परिषद या नियामक बोर्ड, का प्राथमिक उद्देश्य किसे सुगम बनाना है?
(A) तीव्र कार्यकारी कार्यवाही।
(B) सामूहिक विचार-विमर्श और निर्णय लेना।
(C) व्यावसायिक लाभ।
(D) गुप्त सूचना अभियान।

61. किसी संगठन में 'लाइन और स्टाफ के बीच संघर्ष' प्रायः इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि:
(A) लाइन अधिकारियों के पास ज्ञान के बिना अधिकार होता है, जबकि स्टाफ अधिकारियों के पास अधिकार के बिना ज्ञान होता है।
(B) लाइन अधिकारी सामान्यज्ञ होते हैं, जबकि स्टाफ अधिकारी विशेषज्ञ होते हैं।
(C) स्टाफ एजेंसियों को प्रायः लगता है कि उनकी सलाह को लाइन एजेंसियों द्वारा उपेक्षित किया जाता है।
(D) उपर्युक्त सभी।

62. निम्नलिखित प्रमुख प्रकाशनों और विचारों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें:
1. हर्बर्ट साइमन की "एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर"
2. वुड्रो विल्सन की "द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन"
3. हाथोर्न प्रयोग
4. फ्रेड रिग्स की "द इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन"
(A) 2, 3, 1, 4
(B) 1, 2, 3, 4
(C) 2, 1, 3, 4
(D) 3, 2, 4, 1

की गई। इसका अर्थ है कि पूरे देश पर एक ही संविधान और सरकार का कानून प्रभावी हो। यह एकीकरण एक मजबूत राष्ट्र-राज्य की आधारशिला है जिसके बिना आर्थिक विकास संभव नहीं था।

290. (A) के.टी. शाह
संविधान सभा के सदस्य के.टी. शाह ने नीति निदेशक तत्वों की आलोचना करते हुए इसे 'बैंक पर एक चेक, जिसका भुगतान संसाधनों की अनुमति पर निर्भर है' कहा था। उनका यह तर्क इस तथ्य पर आधारित था कि ये तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं और इनका कार्यान्वयन पूर्णतः सरकार की इच्छा और उपलब्ध आर्थिक संसाधनों पर निर्भर करता है। यद्यपि यह आलोचना विधिक बाध्यता की कमी को दर्शाती है, परंतु समय के साथ ये तत्व सरकारों हेतु कल्याणकारी नीतियों के निर्माण का मुख्य आधार सिद्ध हुए हैं, जो शासन की मानवीय दिशा निर्धारित करते हैं।

291. (C) कार्यपालिका विधायिका से ली जाती है और उसके प्रति उत्तरदायी होती है।
भारतीय संसदीय प्रणाली 'शक्तियों के संलयन' पर आधारित है। यहाँ कार्यपालिका (मंत्रिपरिषद) का गठन अनिवार्य रूप से विधायिका (संसद) के सदस्यों में से ही किया जाता है। यदि कोई मंत्री सदन का सदस्य नहीं है, तो उसे छह महीने के भीतर सदस्यता लेनी पड़ती है। इसके अलावा, कार्यपालिका अपनी नीतियों हेतु निरंतर विधायिका के विश्वास पर निर्भर रहती है। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि सरकार और संसद के बीच निरंतर सहयोग बना रहे, जिससे शासन में दक्षता और जवाबदेही दोनों सुनिश्चित होती हैं। यह व्यवस्था सरकार को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाती है।

292. (D) राष्ट्रीय विकास परिषद
राष्ट्रीय विकास परिषद (एन.डी.सी.) एक 'संविधानोतर' निकाय है, जिसका गठन 1952 में किया गया था। इसमें प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। इसका मुख्य कार्य पंचवर्षीय योजनाओं की समीक्षा करना और आर्थिक नीतियों पर केंद्र एवं राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करना था। यद्यपि अब नीति आयोग ने इसकी भूमिका को प्रतिस्थापित कर दिया है, परंतु यह लंबे समय तक सहकारी संघवाद और सहभागी नियोजन हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मंच बना रहा, जिसने विकास के एजेंडे पर राज्यों के बीच व्यापक सहमति को निरंतर बढ़ावा दिया।

293. (D) किसी व्यक्ति को सार्वजनिक पद धारण करने से रोकना जिसका वह वैधानिक रूप से हकदार नहीं है।
'अधिकार-पृच्छा' की रिट का शाब्दिक अर्थ है 'किस अधिकार से'। यह रिट न्यायालय द्वारा तब जारी की जाती है जब उसे लगता है कि कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद पर अवैध रूप से आसीन है। इस रिट के माध्यम से न्यायालय उस व्यक्ति से उसके दावे की वैधता पूछता है। यदि यह पाया जाता है कि उसकी नियुक्ति नियमानुसार नहीं हुई है, तो न्यायालय उसे पद छोड़ने का आदेश दे सकता है। यह रिट सार्वजनिक पदों के दुरुपयोग को रोकने और यह सुनिश्चित करने का साधन है कि सरकारी नियुक्तियां पारदर्शी और विधिक रूप से पूर्णतः सही हों।

294. (B) गठबंधन की राजनीति और अधिक संघीय सौदेबाजी।
1980 के दशक के उत्तरार्ध से क्षेत्रीय दलों के बढ़ते प्रभाव ने सत्ता के ढांचे को बदल दिया। किसी भी एक राष्ट्रीय दल हेतु पूर्ण बहुमत प्राप्त करना कठिन हुआ, जिससे 'गठबंधन युग' शुरू हुआ। इस स्थिति में, क्षेत्रीय दलों ने अपनी शर्तों पर केंद्र सरकार का समर्थन किया, जिससे राष्ट्रीय नीति निर्माण में राज्यों के विशिष्ट हितों को अधिक महत्व मिलने लगा। इसे 'सौदेबाजी वाला संघवाद' भी कहा जाता है, जहाँ राज्यों ने केंद्र से अधिक वित्तीय सहायता और स्वायत्तता की मांग की। इसने भारतीय संघवाद को अधिक विविधतापूर्ण और वास्तव में प्रतिनिधित्ववादी बनाया है।

295. (A) 3, 1, 4, 2
संविधान के संशोधनों का सही कालानुक्रमिक क्रम प्रथम संशोधन (1951) से शुरू होता है। इसके बाद ऐतिहासिक 42वां संशोधन (1976) आया जिसे 'लघु-संविधान' कहा जाता है। तत्पश्चात, 44वां संशोधन (1978) लाया गया जिसने आपातकाल की ज्यादतियों को सुधारा। अंत में, 1992 में 73वां संशोधन पारित हुआ जिसने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। यह क्रम भारतीय संवैधानिक यात्रा के विभिन्न पड़ावों - शुरुआती सुधारों से लेकर स्थानीय स्वशासन के सुदृढ़ीकरण तक के इतिहास को प्रदर्शित करता है, जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण है।

296. (A) किसी विशेष हित को बढ़ावा देने के लिए समाचार लेखों के रूप में छद्म विज्ञापन।
'पेड न्यूज़' भारतीय लोकतंत्र हेतु एक गंभीर चुनौती है। यह एक ऐसी प्रथा है जहाँ राजनीतिक दल धन देकर समाचारों में अपने पक्ष में सामग्री प्रकाशित करवाते हैं, जिसे सामान्य समाचार की तरह प्रस्तुत किया जाता है। मतदाता इसे निष्पक्ष समाचार मानकर भ्रमित हो जाते हैं, जबकि वास्तव में वह एक प्रायोजित विज्ञापन होता है। यह चुनावी निष्पक्षता को प्रभावित करता है और जनमत को अनुचित रूप से मैनिपुलेट करता है। निर्वाचन आयोग इसे रोकने हेतु निरंतर प्रयास कर रहा है ताकि मीडिया की विश्वसनीयता बनी रहे और जनता को सही सूचना प्राप्त हो सके।

297. (C) मुस्लिम समुदाय
2005 में न्यायमूर्ति राजिंदर सच्चर की अध्यक्षता वाली समिति ने भारतीय मुस्लिम समुदाय की सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति का व्यापक अध्ययन किया। समिति की रिपोर्ट ने खुलासा किया कि कई क्षेत्रों में मुस्लिमों की स्थिति अत्यंत चिंताजनक थी। रिपोर्ट ने सरकारी नौकरियों और शिक्षा में उनके कम प्रतिनिधित्व को रेखांकित किया। इसने उनके उत्थान हेतु विशेष विकासात्मक योजनाओं और समावेशी नीतियों की सिफारिश की। इस रिपोर्ट ने भारत में अल्पसंख्यकों के विकास और सामाजिक न्याय की बहस को एक नया तथ्यात्मक आधार प्रदान किया, जिससे नीतिगत बदलावों की आवश्यकता स्पष्ट हुई।

Downloaded from www.pdf.tube

प्राप्त करता है और जिसे वह आउटपुट प्रदान करता है।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

75. "मुख्य विधायक" (chief legislator) के रूप में मुख्य कार्यपालिका की भूमिका में सम्मिलित है:
(A) विधायी सदन की अध्यक्षता करना।
(B) बराबर मत होने की स्थिति में निर्णायक मत देना।
(C) संदेशों, वीटो और नीति प्रस्तावों के माध्यम से विधि निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करना।
(D) विधायिका के सदस्यों की नियुक्ति करना।

76. रिग्स के पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण के संदर्भ में, "अतिव्यापन" (overlapping) उस स्थिति को संदर्भित करता है जहाँ:
(A) सरकार और निजी क्षेत्र समान कार्य करते हैं।
(B) आधुनिक विशिष्ट संरचनाएं उपस्थित हैं, लेकिन पुरानी अविभेदित संरचनाएं उन कार्यों को करना जारी रखती हैं।
(C) केंद्र और स्थानीय सरकारों के कार्यों में महत्वपूर्ण अतिव्यापन होता है।
(D) विभिन्न प्रशासनिक भूमिकाओं के लिए कार्य विवरण स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं हैं।

77. निम्नलिखित में से कौन एक अनौपचारिक संगठन की प्रमुख विशेषता है?
(A) यह प्रबंधन द्वारा आधिकारिक रूप से स्वीकृत होता है।
(B) यह व्यक्तिगत संबंधों और सामाजिक नेटवर्क पर आधारित होता है।
(C) यह औपचारिक संगठन के लक्ष्यों के लिए सदैव हानिकारक होता है।
(D) इसकी एक स्पष्ट रूप से परिभाषित और स्थिर संरचना होती है।

78. पूरी तरह से नवीन बाजार में एक नई उत्पाद श्रेणी प्रारंभ करने का निर्णय किसका उदाहरण है?
(A) अनियोजित निर्णय (Non-programmed decision)
(B) नियोजित निर्णय (Programmed decision)
(C) नियमित निर्णय
(D) प्रक्रियात्मक निर्णय

79. विदेश मंत्रालय के लिए एक सरकारी विभाग किसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है?
(A) स्टाफ एजेंसी
(B) सहायक एजेंसी
(C) लोक निगम
(D) लाइन एजेंसी

80. विकास प्रशासन का एक प्रमुख उद्देश्य किस प्रशासनिक क्षमता को बढ़ाना है?
(A) पारंपरिक सामाजिक संरचनाओं को बनाए रखना।
(B) राष्ट्रीय विकास के लिए योजनाओं और कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना।
(C) औपनिवेशिक प्रशासनिक तंत्र का विस्तार करना।
(D) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विनियमित करना।

81. एक 'लंबवत' (tall) संगठनात्मक संरचना की विशेषता है:
(A) नियंत्रण का एक संकीर्ण क्षेत्र और कई पदसोपानिक स्तर।
(B) नियंत्रण का एक विस्तृत क्षेत्र और कुछ पदसोपानिक स्तर।
(C) पदसोपानिक स्तरों का पूर्ण अभाव।
(D) विकेंद्रीकृत निर्णय प्रक्रिया।

82. चेस्टर बर्नार्ड द्वारा प्रस्तुत 'उदासीनता का क्षेत्र' (zone of indifference) की अवधारणा किसे संदर्भित करती है?
(A) वह क्षेत्र जहाँ श्रमिक सबसे कम उत्पादक होते हैं।
(B) आदेशों की वह सीमा जिसे एक कर्मचारी सचेत रूप से प्राधिकार पर प्रश्न उठाए बिना स्वीकार करने को तत्पर है।
(C) कार्यालय में वह भौतिक स्थान जहाँ कोई कार्य नहीं होता है।
(D) एक बाजार खंड जो विज्ञापन के प्रति अनुत्तरदायी है।

83. पदसोपान (Hierarchy) के सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. इसे सोपानिक सिद्धांत (scalar principle) के रूप में भी जाना जाता है।
2. यह उत्तरदायित्व के लिए आदेश की एक स्पष्ट श्रृंखला सुनिश्चित करता है।
3. यह तीव्र संचार के लिए 'लेवल जंपिंग' को प्रोत्साहित करता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1
(D) 1, 2 और 3

84. संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री किसका एक उदाहरण है?
(A) एक वास्तविक कार्यपालिका जो राज्य का प्रमुख भी है।
(B) एक वास्तविक कार्यपालिका जो राज्य का प्रमुख नहीं है।
(C) एक नाममात्र की कार्यपालिका।
(D) एक बहुल कार्यपालिका।

85. लोक निगम सामान्यतः किसके द्वारा बनाए जाते हैं?
(A) मुख्य कार्यपालिका का एक कार्यकारी आदेश।
(B) निदेशक मंडल का एक प्रस्ताव।
(C) विधायिका का एक विशिष्ट अधिनियम।
(D) एक न्यायिक डिक्री।

NODIA

(B) परिवर्तन-केंद्रित
(C) प्रक्रिया-उन्मुख
(D) ग्राहक-केंद्रित

109. प्रशासन के प्रति व्यवस्था दृष्टिकोण (Systems approach) किस शैक्षणिक विषय से अत्यधिक प्रभावित था?
(A) इतिहास
(B) विधि
(C) जीव विज्ञान
(D) साहित्य

110. कौन सा कथन लोक निगम की प्रकृति का त्रुटिपूर्ण वर्णन करता है?
(A) यह पूर्णतः राज्य के स्वामित्व में होता है।
(B) यह अपने दैनिक कार्यों में पर्याप्त स्वायत्तता प्राप्त करता है।
(C) यह सामान्यतः एक व्यावसायिक उपक्रम के प्रबंधन के लिए बनाया जाता है।
(D) इसके कर्मचारियों को सामान्यतः मानक सिविल सेवा नियमों के अधीन सिविल सेवक माना जाता है।

111. 'ग्रेपवाइन' (grapevine) किसमें संचार का प्राथमिक माध्यम है?
(A) औपचारिक संगठन
(B) नौकरशाही संगठन
(C) लाइन और स्टाफ संगठन
(D) अनौपचारिक संगठन

112. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:
अभिकथन (A): नियंत्रण का बहुत संकीर्ण क्षेत्र सूक्ष्म-प्रबंधन (micromanagement) और मंद संचार का कारण बन सकता है।
कारण (R): संकीर्ण क्षेत्र के साथ, प्रबंधन के कई स्तर होते हैं, और वरिष्ठ अपने अधीनस्थों के कार्य में बहुत गहराई से सम्मिलित हो सकते हैं।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

113. विदेश नीति में राष्ट्र के नेता के रूप में मुख्य कार्यपालिका की भूमिका को क्या कहा जाता है?
(A) मुख्य प्रशासक
(B) मुख्य विधायक
(C) मुख्य राजनयिक (Chief Diplomat)
(D) कमांडर-इन-चीफ

114. फ्रेड रिग्स के अनुसार, 'साला' (Sala) मॉडल किसका एक प्रशासनिक उपतंत्र है?
(A) संगलन समाज (Fused society)
(B) विवर्तित समाज (Diffracted society)
(C) प्रिज्मीय समाज (Prismatic society)
(D) कृषि प्रधान समाज

115. हर्बर्ट साइमन की "सीमित तर्कसंगतता" का अर्थ है कि निर्णय लेने वाले:
(A) तर्कसंगत हैं, लेकिन अपनी सूचना और संज्ञानात्मक क्षमताओं की सीमा के भीतर।
(B) पूरी तरह से तर्कहीन हैं।
(C) पूर्ण तर्कसंगतता प्राप्त करने में सक्षम हैं।
(D) केवल भावनात्मक कारकों से प्रभावित होते हैं।

116. 'किचन कैबिनेट' या मुख्य कार्यपालिका के सलाहकारों के एक अनौपचारिक समूह का अस्तित्व किसका उदाहरण है?
(A) कार्यशील औपचारिक संगठन।
(B) शासन पर अनौपचारिक संगठन का प्रभाव।
(C) पदसोपान का सिद्धांत।
(D) स्टाफ एजेंसियों की विफलता।

117. एक संगठनात्मक चार्ट मुख्य रूप से क्या दर्शाता है?
(A) संगठन के भीतर अनौपचारिक संबंध।
(B) औपचारिक संरचना, अधिकार की रेखाएं और रिपोर्टिंग संबंध।
(C) अनौपचारिक माध्यमों (grapevine) का संचार प्रवाह।
(D) व्यक्तिगत प्रभाव पर आधारित शक्ति की गतिशीलता।

118. संगठन का कौन सा सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक वस्तु के लिए एक स्थान होना चाहिए और प्रत्येक वस्तु अपने स्थान पर होनी चाहिए?
(A) व्यवस्था (Order)
(B) समता (Equity)
(C) पहल (Initiative)
(D) सहयोग की भावना (Esprit de corps)

119. विकास प्रशासन के लिए एक प्रमुख चुनौती है:
(A) सभी प्रकार के परिवर्तनों का विरोध करना।
(B) लोकतांत्रिक मूल्यों और भागीदारी के साथ तीव्र विकास को संतुलित करना।
(C) विशेष रूप से राजस्व संग्रह पर ध्यान केंद्रित करना।
(D) नागरिकों के साथ अंतःक्रिया कम करना।

120. निम्नलिखित में से कौन मैक्स वेबर द्वारा पहचाने गए प्राधिकार (authority) के तीन प्रकारों में से एक नहीं है?
(A) पारंपरिक प्राधिकार
(B) करिश्माई प्राधिकार
(C) कानूनी-तर्कसंगत प्राधिकार
(D) लोकतांत्रिक प्राधिकार

121. 'सहायक एजेंसी' (auxiliary agency) का मुख्य कार्य है:
(A) सीधे जनता की सेवा करना।

Click Here to Buy book on Amazon

व्यक्तियों के सामाजिक संबंधों से स्वतः उत्पन्न होता है।
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
(D) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।

99. व्यवस्था दृष्टिकोण (Systems view) में, 'नकारात्मक एन्ट्रॉपी' (negative entropy) या 'नेगएन्ट्रॉपी' क्या है?
(A) प्रणालियों की अव्यवस्था में गिरावट की प्राकृतिक प्रवृत्ति।
(B) व्यवस्था का अंतिम आउटपुट।
(C) वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई व्यवस्था अपनी संरचना बनाए रखने के लिए व्यय की गई ऊर्जा से अधिक ऊर्जा आयात करती है।
(D) फीडबैक लूप जो विचलनों को ठीक करता है।

100. निम्नलिखित विचारधाराओं को संगठन सिद्धांत में उनकी प्रमुखता के क्रम में व्यवस्थित करें:
1. व्यवहारवाद (साइमन)
2. मानव संबंध (मेयो)
3. वैज्ञानिक प्रबंधन (टेलर)
4. आकस्मिकता सिद्धांत
(A) 3, 2, 1, 4
(B) 1, 2, 3, 4
(C) 2, 3, 1, 4
(D) 3, 1, 2, 4

101. निर्णय लेने वाला मॉडल जो यह मानता है कि निर्णय लेने वाले पूर्णतः तर्कसंगत हैं और उनके पास पूर्ण सूचना है, क्या कहलाता है?
(A) संतोषप्रद (Satisficing) मॉडल
(B) वृद्धिशील (Incremental) मॉडल
(C) तर्कसंगत-व्यापक मॉडल (Rational-Comprehensive Model)
(D) गार्बेज कैन मॉडल

102. संगठन का कौन सा रूप एक विभाग के सार्वजनिक उद्देश्य को एक निजी कंपनी के परिचालन लचीलेपन के साथ जोड़ता है?
(A) एक नियामक आयोग
(B) एक स्टाफ एजेंसी
(C) एक लोक निगम
(D) एक अनौपचारिक समूह

103. रिग्स के मॉडल में, एक 'संग्लन' (fused) समाज वह है जो:
(A) पारंपरिक और अविभेदित है, जहाँ एक ही संरचना कई कार्य करती है।
(B) आधुनिक और अत्यधिक विभेदित है।
(C) पारंपरिक और आधुनिक तत्वों का मिश्रण है।
(D) निरंतर सामाजिक संघर्ष की स्थिति में है।

104. सूची I को सूची II के साथ सुमेलित कीजिए:

सूची I (संगठनात्मक विशेषता):
P. वरिष्ठ-अधीनस्थ संबंध
Q. एक वरिष्ठ के अधीन अधीनस्थों की संख्या
R. विशिष्ट सलाहकार कार्य
S. अधिकार का प्रसार।

सूची II (संबद्ध अवधारणा):
1. नियंत्रण का क्षेत्र
2. स्टाफ
3. पदसोपान
4. विकेंद्रीकरण।

(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-3, Q-1, R-2, S-4
(C) P-3, Q-2, R-1, S-4
(D) P-4, Q-1, R-2, S-3

105. मुख्य कार्यपालिका की राजनीतिक भूमिका में सम्मिलित है:
(A) विभागीय प्रमुखों का पर्यवेक्षण करना।
(B) अपने राजनीतिक दल के नेता के रूप में कार्य करना।
(C) क्षमादान और दंड कम करना।
(D) वार्षिक बजट तैयार करना।

106. 'आदेश की एकता' (Unity of Commऔर) और 'निर्देशन की एकता' (Unity of Direction) के बीच एक प्रमुख अंतर यह है कि:
(A) आदेश की एकता एक अधीनस्थ से संबंधित है; निर्देशन एक योजना से संबंधित है।
(B) निर्देशन की एकता एक शास्त्रीय सिद्धांत है, जबकि आदेश आधुनिक है।
(C) ये अलग-अलग शब्दावली का उपयोग करके वर्णित समान अवधारणाएं हैं।
(D) आदेश की एकता संरचना से संबंधित है, जबकि निर्देशन प्रक्रिया से संबंधित है।

NODIA

107. अनौपचारिक संगठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. दक्षता में सुधार के लिए इसे शीर्ष प्रबंधन द्वारा जानबूझकर बनाया जाता है।
2. यह सामाजिक मानदंडों, रीति-रिवाजों और मित्रता के माध्यम से संचालित होता है।
3. यह औपचारिक संगठन के लक्ष्यों का समर्थन कर सकता है या उनके विरुद्ध कार्य कर सकता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3

108. विकास प्रशासन को प्रायः 'कार्य-उन्मुख' और 'परिणाम-उन्मुख' के रूप में वर्णित किया जाता है, जो इसे पारंपरिक प्रशासन से पृथक करता है जो है:
(A) लक्ष्य-केंद्रित

158. मुख्य कार्यपालिका के कार्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति और उन्हें पदमुक्त करना।
2. प्रशासन का निर्देशन और पर्यवेक्षण।
3. देश के सभी कानूनी विवादों का अंतिम अधिनिर्णय।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3

159. रिग्स के मॉडल में एक "संगलन" (fused) समाज उन संरचनाओं की विशेषता है जो हैं:
(A) अत्यधिक विभेदित
(B) विशिष्ट
(C) बहु-कार्यात्मक
(D) आधुनिक

160. नगर प्रशासन में 'लाइन' इकाई का सबसे अच्छा उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है?
(A) अग्निशमन विभाग
(B) वित्त विभाग
(C) विधि विभाग
(D) मानव संसाधन विभाग

161. संगठन के आकस्मिकता सिद्धांत (contingency theory) का मुख्य तर्क यह है कि:
(A) सभी संगठनों को प्रबंधित करने का एक ही सर्वोत्तम विधि है।
(B) सर्वोत्तम संगठनात्मक संरचना विभिन्न स्थितिजन्य कारकों पर निर्भर करती है।
(C) सभी संगठनों को विकेंद्रीकृत किया जाना चाहिए।
(D) औपचारिक संगठन की तुलना में अनौपचारिक संगठन अधिक महत्वपूर्ण है।

162. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन I: अधिकार के केंद्रीकरण से संकट की स्थिति में तीव्रता से निर्णय लिए जा सकते हैं।
कथन II: अधिकार का विकेंद्रीकरण कर्मचारियों को सशक्त बनाता है और कार्य संतुष्टि बढ़ा सकता है।
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
(D) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।

163. 'विकास प्रशासन' (Development Administration) और 'प्रशासनिक विकास' (Administrative Development) के बीच एक प्रमुख अंतर है:
(A) कोई अंतर नहीं है; ये शब्द पर्यायवाची हैं।
(B) प्रशासनिक विकास विकासशील देशों के लिए है।
(C) विकास प्रशासन कार्यक्रमों का प्रशासन है; प्रशासनिक विकास क्षमता का निर्माण है।
(D) विकास प्रशासन लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करता है।

164. 'संतोषप्रद' (satisficing) की अवधारणा किसकी शास्त्रीय आर्थिक धारणा को सीधी चुनौती है?
(A) लाभ अधिकतमकरण (Profit maximization)
(B) सीमित तर्कसंगतता
(C) श्रम विभाजन
(D) अदृश्य हाथ (The invisible hऔर)

165. भारत का राष्ट्रपति किसका एक उदाहरण है?
(A) वास्तविक कार्यपालिका
(B) बहुल कार्यपालिका
(C) वंशानुगत कार्यपालिका
(D) नाममात्र की कार्यपालिका

166. व्यावसायिक सिद्धांतों पर संचालित एक सरकारी स्वामित्व वाली रेलवे प्रणाली को किसके रूप में सबसे अच्छी तरह से संगठित किया जाता है?
(A) विभाग
(B) लोक निगम
(C) परिषद
(D) स्टाफ इकाई

167. संगठन के भीतर अनौपचारिक संचार नेटवर्क को लोकप्रिय रूप से किस रूप में जाना जाता है?
(A) सोपानिक श्रृंखला
(B) ग्रेपवाइन (The grapevine)
(C) गैंगप्लैंक
(D) फीडबैक लूप

168. निम्नलिखित में से कौन एक "लंबवत" (tall) संगठन संरचना की विशेषता है?
(A) नियंत्रण का विस्तृत क्षेत्र
(B) प्रबंधन के कई स्तर
(C) ऊपर से नीचे तक तीव्र संचार
(D) कर्मचारी स्वायत्तता का उच्च स्तर

169. लोक प्रशासन के एक विषय के रूप में विकास के प्रारंभिक चरण में किसका प्रभुत्व था?
(A) मानव संबंध आंदोलन
(B) व्यवस्था दृष्टिकोण
(C) राजनीति-प्रशासन द्विभाजन
(D) विकास प्रशासन की अवधारणा

170. संयुक्त राज्य अमेरिका के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों को उनकी अध्यक्षता के कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें:
1. वुड्रो विल्सन
2. फ्रैंकलिन डी. रुजवेल्ट
3. थियोडोर रुजवेल्ट
4. एंड्रयू जैक्सन

Downloaded from www.pdf.tube

(B) अन्य विभागों को सामान्य हाउसकीपिंग और संस्थागत सेवाएं प्रदान करना।
(C) नीति पर मुख्य कार्यपालिका को परामर्श देना।
(D) सरकार के प्राथमिक मिशन को निष्पादित करना।

122. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन I: पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण तर्क देता है कि प्रशासनिक समाधानों को सीधे विकसित देशों से विकासशील देशों में प्रत्यारोपित किया जा सकता है।
कथन II: फ्रेड रिग्स ने स्थानीय 'पारिस्थितिकी' पर विचार करने की आवश्यकता पर बल देते हुए, प्रशासनिक मॉडलों के अंधानुकरण के विरुद्ध चेतावनी दी थी।
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
(D) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।

123. प्रबंधन के 14 सिद्धांतों के साथ कौन सा सिद्धांतकार जुड़ा हुआ है?
(A) फ्रेडरिक टेलर
(B) मैक्स वेबर
(C) एल्टन मेयो
(D) हेनरी फेयोल

124. संगठन के 'परिषद' (Council) रूप को सामान्यतः उन गतिविधियों के लिए अनुपयुक्त माना जाता है जिनमें निम्न की आवश्यकता होती है:
(A) विचार-विमर्श और चर्चा।
(B) विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व।
(C) नीति निर्धारण।
(D) गति, गोपनीयता और निर्णायक कार्रवाई।

125. वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक संगठन अपने प्रदर्शन के बारे में सूचना प्राप्त करता है और समायोजन करता है, क्या कहलाती है?
(A) इनपुट
(B) आउटपुट
(C) फीडबैक लूप
(D) एन्ट्रॉपी

126. मुख्य कार्यपालिका की क्षमादान और दंड कम करने की शक्ति एक:
(A) विधायी शक्ति है
(B) प्रशासनिक शक्ति है
(C) अर्ध-न्यायिक शक्ति है
(D) वित्तीय शक्ति है

127. 'राजनीति-प्रशासन द्विभाजन' किसके बीच एक स्पष्ट अंतर का सुझाव देता है?
(A) लाइन और स्टाफ
(B) औपचारिक और अनौपचारिक संगठन
(C) केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण
(D) नीति-निर्माण और नीति-निष्पादन

128. मैट्रिक्स संगठन में एक कर्मचारी जो प्रोजेक्ट मैनेजर और फंक्शनल हेड दोनों को रिपोर्ट करता है, वह किसका उल्लंघन करता है?
(A) नियंत्रण का क्षेत्र
(B) आदेश की एकता
(C) श्रम विभाजन
(D) पदसोपान

129. 'बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम' (Bank Wiring Observation Room) प्रयोग का मुख्य निष्कर्ष क्या था?
(A) उत्पादकता के लिए अनुकूल प्रकाश व्यवस्था का महत्व।
(B) वित्तीय प्रोत्साहनों की प्रभावशीलता।
(C) अनौपचारिक समूह मानदंडों का अस्तित्व जिन्होंने उत्पादन को प्रतिबंधित किया।
(D) लोकतांत्रिक पर्यवेक्षण की श्रेष्ठता।

130. परिसर-व्यापी डेटा उल्लंघन संकट जिसके लिए बिना किसी मिसाल के एक नई रणनीति की आवश्यकता है, किसका उदाहरण है?
(A) नियोजित निर्णय-निर्माण
(B) संतोषप्रद व्यवहार
(C) अनियोजित निर्णय-निर्माण
(D) सोपानिक श्रृंखला का पालन करना

NODIA

131. संगठन के एक आदर्श, कुशल रूप के रूप में 'नौकरशाही' की अवधारणा किसके साथ जुड़ी है?
(A) कार्ल मार्क्स
(B) मैक्स वेबर
(C) रॉबर्ट मिशेल्स
(D) वुड्रो विल्सन

132. वेबर की नौकरशाही के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. कार्यालयों का एक स्पष्ट पदसोपान।
2. नियमों और विनियमों की एक प्रणाली।
3. व्यक्तिगत पक्षपात के आधार पर चयन और पदोन्नति।
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3

133. निम्नलिखित में से कौन 'व्यवस्था सीमा' (systems boundary) का सबसे अच्छा वर्णन करता है?
(A) संगठन के कार्यालय की भौतिक दीवारें।
(B) संगठन को उसके वातावरण से पृथक करने वाली रेखा।
(C) संगठनात्मक पदसोपान का शीर्ष स्तर।

(D) संगठन के औपचारिक नियम और विनियम।

134. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:
अभिकथन (A): विकास प्रशासन के लिए ऐसे प्रशासकों की आवश्यकता होती है जो न केवल कुशल हों बल्कि अभिनव और उद्यमी भी हों।
कारण (R): विकास में परिवर्तन और जटिलता का प्रबंधन सम्मिलित है, जिसके लिए एक कठोर, नियमबद्ध दृष्टिकोण से अधिक की आवश्यकता होती है।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

135. पदसोपान में निचले स्तरों को निर्णय लेने की शक्ति सौंपने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है?
(A) केंद्रीकरण
(B) औपचारिकता
(C) विकेंद्रीकरण
(D) विशेषीकरण

136. 'नाममात्र' (Nominal) मुख्य कार्यपालिका वह है जो:
(A) वास्तविक कार्यकारी शक्ति रखती है।
(B) नाममात्र, अल्पावधि के लिए निर्वाचित होती है।
(C) बहुल कार्यपालिका का भाग है।
(D) पद में राज्य का प्रमुख होती है लेकिन बहुत कम वास्तविक शक्ति का प्रयोग करती है।

137. निम्नलिखित में से कौन संगठन के विभागीय रूप का लाभ नहीं है?
(A) मुख्य कार्यपालिका और विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व की स्पष्ट रेखाएं।
(B) प्रक्रियाओं और मानकों में एकरूपता।
(C) मुख्य कार्यपालिका द्वारा समन्वय की सुविधा।
(D) व्यावसायिक संचालन में उच्च स्तर का लचीलापन और गति।

138. वह सिद्धांत जो किसी कार्य को करने के लिए 'सर्वोत्तम विधि' खोजने हेतु 'समय और गति अध्ययन' पर केंद्रित है, वह है:
(A) मानव संबंध सिद्धांत
(B) वैज्ञानिक प्रबंधन
(C) नौकरशाही सिद्धांत
(D) व्यवस्था सिद्धांत

139. 'सोपानिक सिद्धांत' (Scalar principle) किसकी अवधारणा को संदर्भित करता है?
(A) आदेश की एकता
(B) नियंत्रण का क्षेत्र
(C) पदसोपान (Hierarchy)
(D) लाइन और स्टाफ

140. कौन सा दृष्टिकोण प्रशासनिक प्रक्रिया के भीतर व्यक्तियों के मनोवैज्ञानिक और सामाजिक पहलुओं पर बल देता है?
(A) पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण
(B) व्यवहारवादी दृष्टिकोण
(C) विधिक दृष्टिकोण
(D) ऐतिहासिक दृष्टिकोण

141. पर्यवेक्षक और अधीनस्थ के बीच का संबंध किसका मूलभूत आधार है?
(A) एक अनौपचारिक संगठन
(B) एक लोक निगम
(C) पदसोपान का सिद्धांत
(D) विकेंद्रीकरण का सिद्धांत

142. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन I: एक 'लाइन एजेंसी' की प्राथमिक भूमिका मुख्य कार्यपालिका को लाइन विभागों को नियंत्रित करने में सहायता करना है।
कथन II: एक 'स्टाफ एजेंसी' की प्राथमिक भूमिका परामर्श, योजना और सहायता सेवाएं प्रदान करना है।
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
(D) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।

143. मनोबल और उत्पादकता में सुधार के लिए प्रबंधन को श्रमिकों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, यह विचार किससे संबंधित है?
(A) वेबर का नौकरशाही सिद्धांत।
(B) टेलर का वैज्ञानिक प्रबंधन।
(C) मानव संबंध विचारधारा।
(D) रिग्स का पारिस्थितिकीय मॉडल।

144. एक 'एकल कार्यपालिका' (singular executive) मॉडल, जैसे कि अमेरिकी राष्ट्रपति पद, की विशेषता है:
(A) एक एकल व्यक्ति में अंतिम कार्यकारी प्राधिकार निहित होना।
(B) सदस्यों की एक परिषद के बीच कार्यकारी शक्ति का विभाजन।
(C) कार्यकारी और विधायी शक्तियों का संलयन।
(D) एक मुख्य कार्यपालिका जो केवल एक ही कार्यकाल के लिए कार्य करती है।

145. संगठन सिद्धांत में वी. ए. ग्रेक्युनास का योगदान किस सिद्धांत से संबंधित है?
(A) आदेश की एकता
(B) नियंत्रण का क्षेत्र
(C) पदसोपान
(D) विभागीकरण

Click Here to Buy book on Amazon

146. सूची I को सूची II के साथ सुमेलित कीजिए:
सूची I (संगठन का रूप):
P. विभाग
Q. लोक निगम
R. लाइन एजेंसी
S. स्टाफ एजेंसी।
सूची II (विवरण):
1. विशिष्ट परामर्श और सहायता प्रदान करता है
2. प्राथमिक कार्य (जैसे रक्षा) करता है
3. राजनीतिज्ञ की अध्यक्षता वाली पारंपरिक प्रशासनिक इकाई
4. व्यावसायिक गतिविधियों के लिए स्वायत्त निकाय।
(A) P-3, Q-4, R-2, S-1
(B) P-4, Q-3, R-1, S-2
(C) P-3, Q-1, R-2, S-4
(D) P-1, Q-4, R-2, S-3

147. हर्बर्ट साइमन के अनुसार, मानवीय निर्णय लेने की प्रक्रिया को सबसे अच्छी तरह इस रूप में वर्णित किया गया है:
(A) अधिकतम करना (Maximizing)
(B) इष्टतमीकरण (Optimizing)
(C) संतोषप्रद (Satisficing)
(D) न्यूनतम करना (Minimizing)

148. 'विकास प्रशासन' की अवधारणा को मुख्य रूप से किन विद्वानों द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था?
(A) सोवियत संघ
(B) संयुक्त राज्य अमेरिका
(C) यूनाइटेड किंगडम
(D) जर्मनी

149. एक खुली व्यवस्था (open system), एक बंद व्यवस्था के विपरीत, किसकी विशेषता है?
(A) वातावरण से इसकी पूर्ण स्वतंत्रता।
(B) वातावरण के साथ इसकी अंतःक्रिया और विनिमय।
(C) एक निश्चित और कठोर आंतरिक संरचना।
(D) फीडबैक तंत्र की अनुपस्थिति।

150. 'विकेंद्रीकरण' का एक प्रमुख लाभ यह है कि यह:
(A) पूरे संगठन में कठोर एकरूपता सुनिश्चित करता है।
(B) निचले स्तरों पर त्वरित निर्णय लेने की ओर ले जाता है और कनिष्ठ प्रबंधकों को प्रशिक्षित करता है।
(C) शीर्ष प्रबंधन के लिए समन्वय को सरल बनाता है।
(D) प्रशासन की कुल लागत कम करता है।

151. निम्नलिखित में से कौन 'बहुल कार्यपालिका' (plural executive) का एक संभावित दोष है?
(A) तानाशाही की प्रवृत्ति।
(B) निर्णय लेने में विचार-विमर्श की कमी।
(C) उत्तरदायित्व का प्रसार और निष्क्रियता की संभावना।
(D) अत्यधिक तीव्र और निर्णायक कार्रवाई।

152. "POSDCORB" शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था?
(A) हेनरी फेयोल
(B) लूथर गुलिक
(C) मैक्स वेबर
(D) चेस्टर बर्नार्ड

153. एक नगर का योजना आयोग, जो मेयर को विशेषज्ञ परामर्श प्रदान करता है, किसका उदाहरण है?
(A) लाइन एजेंसी
(B) स्टाफ एजेंसी
(C) लोक निगम
(D) क्षेत्रीय कार्यालय

154. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:
अभिकथन (A): अनौपचारिक संगठन नवाचार और रचनात्मकता का स्रोत हो सकता है।
कारण (R): अनौपचारिक संचार चैनल कभी-कभी औपचारिक चैनलों की तुलना में अधिक तीव्रता से सूचना प्रसारित कर सकते हैं।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

155. 'अल्पतंत्र का लौह नियम' (Iron Law of Oligarchy) किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था?
(A) रॉबर्ट मिशेल्स
(B) मैक्स वेबर
(C) विल्फ्रेडो पेरेटो
(D) गेटानो मोस्का

156. लोक प्रशासन के 'पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण' की मुख्य चिंता है:
(A) प्रशासन के सार्वभौमिक सिद्धांतों की खोज करना।
(B) एक प्रशासनिक प्रणाली और उसके सामाजिक संदर्भ के बीच संबंधों को समझना।
(C) व्यक्तिगत प्रशासकों की निर्णय लेने की प्रक्रिया का विश्लेषण करना।
(D) सरकारी कार्यालयों के भौतिक वातावरण में सुधार करना।

157. कार्यात्मक फोरमैनशिप और मैट्रिक्स संरचनाओं द्वारा किस संगठनात्मक सिद्धांत को चुनौती दी जाती है?
(A) नियंत्रण का क्षेत्र
(B) पदसोपान
(C) आदेश की एकता
(D) केंद्रीकरण

Downloaded from www.pdf.tube

86. संगठन का कौन सा सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि मनुष्य मुख्य रूप से सामाजिक आवश्यकताओं से प्रेरित होते हैं?
(A) मानव संबंध सिद्धांत
(B) नौकरशाही सिद्धांत
(C) वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत
(D) व्यवस्था सिद्धांत

87. निम्नलिखित में से कौन हेनरी फेयोल द्वारा पहचाना गया संगठन का सिद्धांत नहीं है?
(A) कार्य का विभाजन
(B) सीमित तर्कसंगतता
(C) आदेश की एकता
(D) सोपानिक श्रृंखला (Scalar Chain)

88. 'लाइन' और 'स्टाफ' इकाई के बीच मुख्य अंतर किसके संदर्भ में है?
(A) स्थान
(B) आकार
(C) कार्य और अधिकार
(D) बजट

89. नियंत्रण के विस्तृत क्षेत्र वाली एक 'सपाट' (flat) संगठनात्मक संरचना सामान्यतः किसे बढ़ावा देती है?
(A) अधिक पर्यवेक्षण और नियंत्रण।
(B) प्रबंधन के अधिक स्तर।
(C) अधिक कर्मचारी स्वायत्तता और तीव्र संचार।
(D) नियमों का अधिक कठोरता से अनुपालन।

90. लोक प्रशासन के अध्ययन में, 'पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण' प्रशासनिक प्रणालियों के अध्ययन पर बल देता है:
(A) उनके सामाजिक संदर्भ से पृथक होकर।
(B) विशुद्ध रूप से कानूनी नियमों और संरचनाओं के एक समूह के रूप में।
(C) विशिष्ट ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक वातावरण के संबंध में।
(D) व्यक्तिगत निर्णय लेने की प्रक्रियाओं के माध्यम से।

91. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:
अभिकथन (A): आदेश की एकता का सिद्धांत कहता है कि एक अधीनस्थ का केवल एक ही वरिष्ठ होना चाहिए।
कारण (R): इस सिद्धांत का अनुपालन विरोधाभासी आदेशों और निष्ठा की विभाजित भावना को रोकता है।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

92. विकास प्रशासन की सफलता को प्रायः किसके द्वारा मापा जाता है?
(A) प्रक्रियात्मक अनुपालन का स्तर।
(B) वर्ष के अंत में बजट अधिशेष की मात्रा।
(C) साक्षरता, सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक विकास जैसे क्षेत्रों में मूर्त उपलब्धियां।
(D) प्रशासनिक प्रणाली की स्थिरता और अपरिवर्तनीय प्रकृति।

93. एक "सहकारी प्रणाली" (cooperative system) के रूप में संगठन की अवधारणा, जहाँ कार्यपालिका की भूमिका सहयोग सुरक्षित करना है, किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी?
(A) मैक्स वेबर
(B) एफ. डब्ल्यू. टेलर
(C) चेस्टर आई. बर्नार्ड
(D) हर्बर्ट साइमन

94. किसी व्यावसायिक उपक्रम के लिए सरकारी 'विभाग' का सबसे महत्वपूर्ण दोष क्या है?
(A) सार्वजनिक उत्तरदायित्व की कमी।
(B) अत्यधिक स्वायत्तता और लचीलापन।
(C) राजनीतिक हस्तक्षेप और कठोर वित्तीय प्रक्रियाएं।
(D) बड़ी संख्या में कर्मचारियों को नियुक्त करने में असमर्थता।

95. जब राष्ट्रपति जैसा मुख्य कार्यपालिका 'कार्यकारी आदेश' (executive order) जारी करता है, तो यह उनकी किस शक्ति का प्रयोग है?
(A) औपचारिक शक्ति
(B) अर्ध-विधायी शक्ति
(C) न्यायिक शक्ति
(D) दलगत नेतृत्व की भूमिका

NODIA

96. निम्नलिखित में से कौन 'विकेंद्रीकरण' को सबसे अच्छी तरह परिभाषित करता है?
(A) शीर्ष स्तर पर अधिकार का संकेंद्रण।
(B) संगठन के निचले स्तरों पर अधिकार का प्रसार।
(C) एक नए विभाग का सृजन।
(D) राजधानी से दूर सरकारी कार्यालयों का भौतिक स्थानांतरण।

97. हाथोर्न प्रयोग किसके नेतृत्व में संचालित किए गए थे?
(A) हेनरी फेयोल
(B) एल्टन मेयो
(C) मैक्स वेबर
(D) फ्रेडरिक टेलर

98. निम्नलिखित कथनों पर consider कीजिए:
कथन I: औपचारिक संगठन आधिकारिक रूप से स्वीकृत नियमों, संरचनाओं और उद्देश्यों की विशेषता है।
कथन II: अनौपचारिक संगठन औपचारिक संरचना के भीतर

(A) 4, 3, 1, 2
(B) 1, 3, 4, 2
(C) 4, 1, 3, 2
(D) 3, 4, 1, 2

171. संगठन सिद्धांत में, 'एन्ट्रॉपी' (entropy) शब्द एक बंद व्यवस्था की किस प्रवृत्ति को संदर्भित करता है?
(A) बढ़ने और विस्तार करने की।
(B) अव्यवस्था और क्षय की ओर बढ़ने की।
(C) अपने वातावरण के अनुकूल होने की।
(D) संतुलन की स्थिति प्राप्त करने की।

172. अधिकारियों को नियुक्त करने और पदमुक्त करने की मुख्य कार्यपालिका की शक्ति किसके लिए एक महत्वपूर्ण साधन है?
(A) न्यायिक समीक्षा का प्रयोग करना।
(B) प्रशासनिक नियंत्रण और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना।
(C) विदेश नीति का संचालन करना।
(D) राजस्व जुटाना।

173. 'प्रिज्माटिक-साला' (Prismatic-Sala) मॉडल किसमें प्रशासन को समझने के लिए एक सैद्धांतिक निर्माण है?
(A) विकसित देश
(B) साम्यवादी देश
(C) विकासशील देश
(D) प्रागैतिहासिक समाज

174. निम्नलिखित में से कौन संगठन के शास्त्रीय सिद्धांतों की आलोचना नहीं है?
(A) वे बहुत यांत्रिक हैं और मानवीय कारक की उपेक्षा करते हैं।
(B) वे प्रायः अस्पष्ट और विरोधाभासी 'कहावतें' हैं।
(C) वे सार्वभौमिक रूप से लागू नहीं होते हैं।
(D) वे अनौपचारिक समूहों की भूमिका पर अत्यधिक बल देते हैं।

175. एक लोक सेवा आयोग, जो सरकारी भर्ती के लिए मानक निर्धारित करता है, किस रूप में कार्य करता है?
(A) लाइन एजेंसी
(B) केंद्रीय नियंत्रण या स्टाफ एजेंसी
(C) लोक निगम
(D) स्थानीय सरकारी निकाय

176. सूची I को सूची II के साथ सुमेलित कीजिए:
सूची I (विचारक):
P. हर्बर्ट साइमन
Q. फ्रेड रिग्स
R. एल्टन मेयो
S. चेस्टर बर्नार्ड।
सूची II (प्रमुख विचार):
1. हाथोर्न प्रभाव
2. प्रशासन की पारिस्थितिकी
3. सीमित तर्कसंगतता
4. कार्यपालिका के कार्य।
(A) P-2, Q-3, R-1, S-4
(B) P-3, Q-2, R-1, S-4
(C) P-3, Q-2, R-4, S-1
(D) P-1, Q-4, R-2, S-3

177. किसी संगठन में केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण के बीच का चयन किस पर निर्भर करता है?
(A) संगठन का आकार और जटिलता।
(B) अधीनस्थों की क्षमता।
(C) एकरूपता या लचीलेपन की आवश्यकता।
(D) उपर्युक्त सभी।

178. बोर्ड या परिषद का प्राथमिक कार्य प्रायः होता है:
(A) सीधे दिन-प्रतिदिन के कार्यों का प्रबंधन करना।
(B) नीति बनाना, देखरेख प्रदान करना और हितों का प्रतिनिधित्व करना।
(C) सैन्य सटीकता के साथ आदेशों को निष्पादित करना।
(D) विशिष्ट तकनीकी सहायता प्रदान करना।

179. कमांडर-इन-चीफ के रूप में मुख्य कार्यपालिका की भूमिका में किसके ऊपर अधिकार सम्मिलित है?
(A) सिविल सेवा
(B) न्यायपालिका
(C) सशस्त्र बल
(D) राष्ट्रीय विधायिका

180. स्टॉक कम होने पर मानक कार्यालय आपूर्ति को पुनः आदेश देने का निर्णय किसका स्पष्ट उदाहरण है?
(A) एक रणनीतिक निर्णय
(B) एक अनियोजित निर्णय
(C) एक नियोजित निर्णय
(D) एक तर्कहीन निर्णय

181. संगठन सिद्धांत में चेस्टर बर्नार्ड का मुख्य योगदान किस पर उनका बल था?
(A) एक सहकारी सामाजिक प्रणाली के रूप में संगठन।
(B) उत्पादन के तकनीकी पहलू।
(C) नौकरशाही की औपचारिक-विधिक संरचना।
(D) श्रमिकों की तर्कहीनता।

182. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:
अभिकथन (A): लोक निगमों को प्रायः वित्तीय स्वायत्तता प्रदान की जाती है।
कारण (R): इस स्वतंत्रता का उद्देश्य उन्हें व्यावसायिक आधार पर कुशलतापूर्वक संचालित करने की अनुमति देना है।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या

Click Here to Buy book on Amazon

नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

183. जाँच के एक विशिष्ट क्षेत्र के रूप में लोक प्रशासन का अध्ययन किसके सुधार पर ध्यान केंद्रित करने के साथ प्रारंभ हुआ?
(A) अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति
(B) निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र
(C) सरकार और सिविल सेवा
(D) न्यायिक प्रणाली

184. रिग्स के पारिस्थितिकीय मॉडल में 'बहु-कार्यात्मकता' (poly-functionalism) की अवधारणा का अर्थ है:
(A) संरचनाएं अत्यधिक विशिष्ट हैं।
(B) एक ही संरचना कई कार्य करती है।
(C) प्रत्येक कार्य एक ही समर्पित संरचना द्वारा किया जाता है।
(D) कार्य बिल्कुल नहीं किए जाते हैं।

185. 'सपाट' (flat) संगठनात्मक संरचना वह है जिसमें होता है:
(A) नियंत्रण का एक विस्तृत क्षेत्र और कुछ पदसोपानिक स्तर।
(B) कई पदसोपानिक स्तर।
(C) नियंत्रण का एक संकीर्ण क्षेत्र।
(D) आदेश की एक कठोर श्रृंखला।

186. हर्बर्ट साइमन ने संगठन के शास्त्रीय "सिद्धांतों" की आलोचना किस रूप में की है?
(A) वैज्ञानिक नियम
(B) दार्शनिक सत्य
(C) कहावतें (Proverbs)
(D) ऐतिहासिक तथ्य

187. यूनाइटेड किंगडम का प्रधानमंत्री एक 'वास्तविक कार्यपालिका' है जो विधायिका का सदस्य भी है। यह किसकी विशेषता है?
(A) अध्यक्षीय प्रणाली
(B) संसदीय प्रणाली
(C) बहुल कार्यकारी प्रणाली
(D) सत्तावादी प्रणाली

188. एक 'लाइन और स्टाफ' संगठन में, निर्णयों के लिए अंतिम प्राधिकार और उत्तरदायित्व किसके पास होता है?
(A) स्टाफ अधिकारी
(B) line अधिकारी
(C) लाइन और स्टाफ की एक संयुक्त समिति
(D) एक बाहरी परामर्शदाता

189. एक आधुनिक मुख्य कार्यपालिका की भूमिकाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. मुख्य राजनयिक
2. कमांडर-इन-चीफ
3. अपने राजनीतिक दल का नेता

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3

190. एक प्रिज्मीय समाज में 'औपचारिकतावाद' (formalism) का क्या तात्पर्य है?
(A) एक समाज जो औपचारिक समारोहों को महत्व देता है।
(B) नियमों और वास्तविक व्यवहार के बीच उच्च स्तर का सामंजस्य।
(C) निर्धारित मानदंडों और व्यावहारिक वास्तविकता के बीच एक महत्वपूर्ण विसंगति।
(D) नौकरशाही रूपों और कागजी कार्यवाही के प्रति अत्यधिक लगाव।

191. संगठन के एक रूप के रूप में 'विभाग' (Department) का प्राथमिक कार्य है:
(A) सरकार के लिए लाभ उत्पन्न करना।
(B) सरकारी नीति के एक प्रमुख, महत्वपूर्ण क्षेत्र का प्रशासन करना।
(C) अन्य एजेंसियों को परामर्श प्रदान करना।
(D) एक सामूहिक बोर्ड के माध्यम से एक विशिष्ट उद्योग को विनियमित करना।

192. मैरी पार्कर फॉलेट की 'रचनात्मक संघर्ष' (constructive conflict) की अवधारणा बताती है कि संगठन में संघर्ष:
(A) प्रत्येक स्थिति में टाला जाना चाहिए।
(B) संगठनात्मक विफलता का संकेत है।
(C) यदि उचित रूप से प्रबंधित किया जाए, तो नवाचार की ओर ले जाने वाली एक सकारात्मक शक्ति हो सकता है।
(D) सदैव वरिष्ठ द्वारा अपनी इच्छा थोपकर हल किया जाना चाहिए।

193. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन I: व्यवस्था दृष्टिकोण (Systems approach) एक संगठन को एक बंद इकाई के रूप में देखता है।
कथन II: पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण एक प्रणाली और उसके वातावरण के बीच अंतःक्रिया पर बल देता है।
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
(D) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।

194. यह विश्वास कि प्रशासन को राजनीति से पृथक एक विज्ञान बनाया जा सकता है, किसका सार है?
(A) नवीन लोक प्रशासन (The New Public Administration)
(B) राजनीति-प्रशासन द्विभाजन

(C) विकास प्रशासन
(D) पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण

195. निम्नलिखित में से कौन 'नियंत्रण के क्षेत्र' (span of control) को सबसे अच्छी तरह परिभाषित करता है?
(A) वह भौगोलिक क्षेत्र जिसे एक संगठन कवर करता है।
(B) अधीनस्थों की वह संख्या जिसे एक प्रबंधक प्रभावी ढंग से पर्यवेक्षित कर सकता है।
(C) एक संगठन में पदसोपानिक स्तरों की संख्या।
(D) बजट पर प्रबंधक के नियंत्रण की मात्रा।

196. अनौपचारिक संगठन किसकी मानवीय आवश्यकता को पूर्ण करता है?
(A) वित्तीय सुरक्षा
(B) सामाजिक अंतःक्रिया और अपनेपन की भावना
(C) औपचारिक मान्यता और पदसोपान
(D) आदेश की एक स्पष्ट श्रृंखला

197. विकेंद्रीकरण के पक्ष में एक प्रमुख तर्क यह है कि यह:
(A) शीर्ष प्रबंधन के नियंत्रण को सुदृढ़ करता है।
(B) नीति की एकरूपता को बढ़ावा देता है।
(C) निर्णय लेने की प्रक्रिया को कार्य स्थल के समीप लाता है।
(D) निचले स्तरों पर कुशल प्रबंधकों की आवश्यकता को कम करता है।

198. लोक निगम की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है?
(A) दिन-प्रतिदिन के प्रशासनिक विषयों पर प्रत्यक्ष मंत्री नियंत्रण।
(B) सार्वजनिक स्वामित्व, उत्तरदायित्व और व्यावसायिक प्रबंधन सिद्धांतों का मिश्रण।
(C) पूर्णतः वार्षिक विधायी बजट विनियोजन के माध्यम से वित्तपोषण।
(D) सभी कार्मिकों पर मानक सिविल सेवा नियमों का अनिवार्य प्रयोग।

199. जब राष्ट्रपति विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर वीटो करते हैं, तो वे कौन सा कार्य कर रहे होते हैं?
(A) विधायी कार्य
(B) न्यायिक कार्य
(C) प्रशासनिक कार्य
(D) औपचारिक कार्य

200. 'ब्यूरो-पैथोलॉजी' (bureau-pathology) की अवधारणा किसे संदर्भित करती है?
(A) नौकरशाही का आदर्श और कुशल कार्यकरण।
(B) लालफीताशाही और कठोरता जैसे नकारात्मक प्रभाव।
(C) नौकरशाहों के शारीरिक स्वास्थ्य का अध्ययन।
(D) एक नया सरकारी ब्यूरो बनाने की प्रक्रिया।

201. किस सिद्धांत ने यह प्रतिपादित किया कि किसी कार्य को करने की "एक सर्वोत्तम विधि" होती है?
(A) मानव संबंध सिद्धांत
(B) वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत
(C) व्यवस्था सिद्धांत
(D) आकस्मिकता सिद्धांत

202. 'संगलन' और 'विवर्तित' लक्षणों के मिश्रण के रूप में 'प्रिज्मीय' समाज की अवधारणा किस दृष्टिकोण का भाग थी?
(A) निर्णय-निर्माण
(B) पारिस्थितिकीय
(C) व्यवस्था
(D) व्यवहारवादी

203. विकास प्रशासन की एक प्रमुख विशेषता किस पर इसका बल है?
(A) यथास्थिति बनाए रखना।
(B) सामाजिक परिवर्तन के लिए योजना बनाना और उसका प्रबंधन करना।
(C) ऐतिहासिक उदाहरणों का कठोरता से अनुपालन करना।
(D) अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका को कम करना।

204. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:
अभिकथन (A): पदसोपान (hierarchy) का सिद्धांत अधिकांश जटिल संगठनों के लिए मौलिक है।
कारण (R): यह आदेश की एक स्पष्ट श्रृंखला प्रदान करता है, प्रत्यायोजन (delegation) की सुविधा देता है और उत्तरदायित्व निर्धारित करता है।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

205. अनौपचारिक संगठन और इसकी 'ग्रेपवाइन' एक समस्या हो सकती है क्योंकि:
(A) यह अफवाहें और त्रुटिपूर्ण सूचना प्रसारित कर सकता है।
(B) यह सदैव सटीक होता है।
(C) यह औपचारिक चैनलों की तुलना में बहुत मंद है।
(D) यह केवल कार्य से जुड़े विषयों पर चर्चा करता है।

206. 'प्रत्यायोजन' (Delegation) किसकी एक प्रमुख प्रक्रिया है?
(A) केंद्रीकरण
(B) विकेंद्रीकरण
(C) औपचारिकता
(D) विशेषीकरण

207. लोक निगम के लिए निदेशक मंडल संगठन के किस रूप का एक उदाहरण है?

Downloaded from www.pdf.tube

(A) विभाग
(B) लाइन इकाई
(C) परिषद (Council)
(D) स्टाफ इकाई

208. सरकार की संसदीय प्रणाली में 'वास्तविक कार्यपालिका' सामान्यतः होती है:
(A) प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल
(B) सम्राट या राष्ट्रपति
(C) संसद के अध्यक्ष
(D) सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश

209. सेना में स्टाफ कार्य का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है?
(A) युद्ध में एक पैदल सैनिक।
(B) सूचना प्रदान करने वाला एक खुफिया विश्लेषक।
(C) युद्ध के मैदान में एक टैंक कमांडर।
(D) शत्रु पर गोलाबारी करने वाली एक तोपखाना इकाई।

210. सूची I को सूची II के साथ सुमेलित कीजिए:
सूची I (पद):
P. सोपानिक सिद्धांत
Q. आदेश की एकता
R. नियंत्रण का क्षेत्र
S. सहयोग की भावना।
सूची II (अर्थ):
1. एक बॉस को रिपोर्ट करने वाले व्यक्तियों की संख्या
2. एक अधीनस्थ एक बॉस
3. टीम भावना
4. आदेश की श्रृंखला।
(A) P-4, Q-2, R-1, S-3
(B) P-2, Q-4, R-1, S-3
(C) P-4, Q-1, R-2, S-3
(D) P-1, Q-2, R-4, S-3

211. 'नवीन लोक प्रशासन' (New Public Administration) आंदोलन किसके प्रति सरोकार की कमी के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया थी?
(A) दक्षता और मितव्ययिता
(B) सामाजिक समता और प्रासंगिकता
(C) पदसोपानिक संरचनाएं
(D) वैज्ञानिक सिद्धांत

212. हर्बर्ट साइमन ने शास्त्रीय सिद्धांतों की आलोचना करने के लिए 'प्रशासन की कहावतें' (proverbs of administration) शब्द का प्रयोग क्यों किया?
(A) वे बहुत वैज्ञानिक और कठोर थे।
(B) वे अनुभवजन्य रूप से मान्य थे।
(C) वे विरोधाभासी थे और उनमें वैज्ञानिक आधार का अभाव था।
(D) वे मानव मनोविज्ञान पर अत्यधिक केंद्रित थे।

213. लोक निगम बनाने का मुख्य उद्देश्य किसके साथ सार्वजनिक सेवा प्रदान करना है?
(A) अधिक राजनीतिक नियंत्रण।
(B) अधिक व्यावसायिक दक्षता और लचीलापन।
(C) एक सख्त पदसोपानिक संरचना।
(D) जनता के प्रति कम उत्तरदायित्व।

NODIA

214. 'स्वीकृति का क्षेत्र' (zone of acceptance) किस अवधारणा के लिए एक अन्य शब्द है?
(A) कार्यपालिका के कार्य
(B) सहकारी प्रणाली
(C) उदासीनता का क्षेत्र (zone of indifference)
(D) अनौपचारिक संगठन

215. आधुनिक सरकार में 'आदेश की एकता' बनाए रखने में एक प्रमुख चुनौती है:
(A) संगठनों का घटता आकार।
(B) तकनीकी विशेषज्ञों का उदय जो दिशा-निर्देश देते हैं।
(C) सक्षम वरिष्ठों की कमी।
(D) अधिक केंद्रीकरण की ओर झुकाव।

216. "सरकार उचित और सफलतापूर्वक क्या कर सकती है" किसके लिए एक प्रश्न था?
(A) एफ.डब्ल्यू. टेलर
(B) मैक्स वेबर
(C) वुड्रो विल्सन
(D) कार्ल मार्क्स

217. 'औपचारिक संगठन' के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. इसे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जानबूझकर नियोजित और बनाया गया है।
2. इसकी संरचना को सामान्यतः एक संगठनात्मक चार्ट द्वारा प्रदर्शित किया जाता है।
3. यह मुख्य रूप से मित्रता और सामाजिक संबंधों पर आधारित है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1
(D) 1, 2 और 3

218. व्यवस्था दृष्टिकोण (Systems Approach) में, वातावरण _____ का स्रोत है, जिसे संगठन संसाधित करता है।
(A) आउटपुट
(B) इनपुट
(C) थ्रूपुट
(D) एन्ट्रॉपी

219. एक सरकारी विभाग का प्रमुख सामान्यतः होता है:
(A) एक राजनीतिक नियुक्त व्यक्ति या निर्वाचित अधिकारी

(B) एक करियर सिविल सेवक
(C) बिना किसी राजनीतिक संबद्धता वाला एक सामान्यज्ञ प्रबंधक
(D) लोक निगम का प्रमुख

220. 'मुख्य प्रशासक' के रूप में मुख्य कार्यपालिका की प्राथमिक भूमिका है:
(A) यह सुनिश्चित करना कि विधियों को ईमानदारी से कार्यान्वित किया जाए।
(B) अपने राजनीतिक दल का नेतृत्व करना।
(C) अन्य देशों के साथ संधियों पर वार्ता करना।
(D) औपचारिक कार्यों की अध्यक्षता करना।

221. हाथोर्न प्रयोगों ने संगठनात्मक विश्लेषण के ध्यान को किसकी ओर स्थानांतरित कर दिया?
(A) आर्थिक दृष्टिकोण
(B) सामाजिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण
(C) राजनीतिक दृष्टिकोण
(D) विधिक दृष्टिकोण

222. 'बहुल' मुख्य कार्यपालिका की तुलना में 'एकल' मुख्य कार्यपालिका का एक लाभ है:
(A) अधिक विचार-विमर्श
(B) निष्पादन में एकता, ऊर्जा और तत्परता
(C) विविध हितों का बेहतर प्रतिनिधित्व
(D) तानाशाही का कम जोखिम

223. 'लालफीताशाही' (Red tape) किसके साथ जुड़ी एक विकृत अभिव्यक्ति है?
(A) मानव संबंध
(B) नौकरशाही
(C) व्यवस्था सिद्धांत
(D) आकस्मिकता सिद्धांत

224. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन I: विकेंद्रीकरण सदैव अधिक दक्षता की ओर ले जाता है।
कथन II: केंद्रीकरण की इष्टतम मात्रा स्थितिजन्य कारकों पर निर्भर करती है।
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
(D) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।

225. निम्नलिखित में से कौन मुख्य कार्यपालिका के लिए मिंट्ज़बर्ग की प्रबंधकीय भूमिकाओं में से एक नहीं है?
(A) पारस्परिक (Interpersonal)
(B) सूचनात्मक (Informational)
(C) निर्णयात्मक (Decisional)
(D) प्रेरक (Inspirational)

226. रिग्सियन वर्गीकरण में, एक 'विवर्तित' (diffracted) समाज है:
(A) पारंपरिक और अविभेदित।
(B) संक्रमणकालीन और अर्ध-विभेदित।
(C) आधुनिक, विकसित और अत्यधिक विभेदित।
(D) एक सैद्धांतिक असंभवता।

227. यह अवधारणा कि अधिकार संगठन के शीर्ष से नीचे की ओर प्रवाहित होता है, किसके लिए केंद्रीय है?
(A) अधिकार का स्वीकृति सिद्धांत
(B) पदसोपान (hierarchy) का सिद्धांत
(C) अनौपचारिक संगठन
(D) व्यवस्था दृष्टिकोण

228. 'विकास प्रशासन' की एक प्रमुख विशेषता 'ग्राहक' पर ध्यान केंद्रित करना है, जिसका अर्थ है कि इसे होना चाहिए:
(A) नागरिकों की आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायी।
(B) अपने ग्राहकों द्वारा नियंत्रित।
(C) केवल भुगतान करने वाले ग्राहकों पर केंद्रित।
(D) जनमत के प्रति उदासीन।

229. यह विचार कि प्रबंधक के नियंत्रण का क्षेत्र संबंधों में ज्यामितीय वृद्धि से सीमित होता है, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था?
(A) लिंडाल उर्विक
(B) हेनरी फेयोल
(C) वी. ए. ग्रेक्युनास
(D) हर्बर्ट साइमन

230. विश्वविद्यालय का बोर्ड ऑफ रीजेंट्स (Board of Regents) किस संगठनात्मक रूप का उदाहरण है?
(A) विभाग
(B) लोक निगम
(C) परिषद (Council)
(D) लाइन एजेंसी

231. 'लाइन' और 'स्टाफ' इकाइयों के बीच संघर्ष प्रायः उनके अलग-अलग किस कारण से होता है?
(A) लिंग
(B) अभिविन्यास, दृष्टिकोण और प्राधिकार के प्रकार
(C) आयु
(D) शैक्षणिक योग्यता

232. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:
अभिकथन (A): राजनीति-प्रशासन द्विभाजन की भारी आलोचना की गई है।
कारण (R): वास्तव में, प्रशासक नीति-निर्माण की प्रक्रिया में गहराई से सम्मिलित होते हैं।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या

Click Here to Buy book on Amazon

258. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:
अभिकथन (A): मनोबल सुधारने के लिए प्रबंधन द्वारा अनौपचारिक संगठन का उपयोग किया जा सकता है।
कारण (R): प्रबंधक सकारात्मक सूचना प्रसारित करने के लिए 'ग्रेपवाइन' (grapevine) का प्रयोग कर सकते हैं।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

259. बजट तैयार करने की मुख्य कार्यपालिका की शक्ति किसका एक साधन है?
(A) न्यायिक नियंत्रण
(B) प्रशासनिक और राजनीतिक नियंत्रण
(C) औपचारिक नेतृत्व
(D) अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति

260. यह विचार कि प्रशासन "व्यक्तियों के माध्यम से कार्य करवाने" के बारे में है, किसे रेखांकित करता है?
(A) शास्त्रीय सिद्धांत
(B) मानव संबंध और व्यवहारवाद
(C) विधिक-संस्थावाद
(D) आर्थिक सिद्धांत

261. फ्रेड रिग्स की शब्दावली में, संयुक्त राज्य अमेरिका किसका उदाहरण है?
(A) संग्लन समाज
(B) प्रिज्मीय समाज
(C) विवर्तित समाज
(D) कृषि प्रधान समाज

262. संगठन के विभागीय रूप का मुख्य लाभ है:
(A) अधिकतम उत्तरदायित्व और नियंत्रण
(B) अधिकतम लचीलापन
(C) अधिकतम लाभप्रदता
(D) अधिकतम स्वायत्तता

263. नौकरशाही के संभावित दुष्परिणामों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. लालफीताशाही
2. लक्ष्य विस्थापन (Goal Displacement)
3. निर्वैयक्तिकता (Impersonality)
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3

264. 'आदेश की एकता' के सिद्धांत को उन संगठनों में चुनौती दी जाती है जो उपयोग करते हैं:
(A) एक सख्त पदसोपानिक संरचना
(B) एक मैट्रिक्स या परियोजना-आधारित संरचना
(C) नियंत्रण का एक बहुत संकीर्ण क्षेत्र
(D) अत्यधिक केंद्रीकृत निर्णय प्रक्रिया

NODIA

265. 'विकास प्रशासन' को पारंपरिक प्रशासन से क्या पृथक करता है?
(A) परिवर्तन और सामाजिक-आर्थिक प्रगति पर इसका ध्यान।
(B) राजस्व संग्रह के साथ इसकी विशेष चिंता।
(C) प्राचीन काल में इसकी उत्पत्ति।
(D) योजना का इसका तिरस्कार।

266. परामर्श देने के लिए किसी मंत्रालय से जुड़े 'थिंक टैंक' (think tank) किसका उदाहरण है?
(A) लाइन इकाई
(B) स्टाफ इकाई
(C) सार्वजनिक उद्यम
(D) क्षेत्रीय कार्यालय

267. राजनीति-प्रशासन द्विभाजन की समाप्ति इस मान्यता के साथ जुड़ी है कि:
(A) राजनीति और प्रशासन आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं।
(B) प्रशासन एक विशुद्ध विज्ञान हो सकता है।
(C) राजनीति एक अनावश्यक बुराई है।
(D) सभी प्रशासकों का निर्वाचन होना चाहिए।

268. एक संगठन जो फीडबैक को संसाधित करके सीखता है और अनुकूलन करता है, किसकी अवधारणा है?
(A) शास्त्रीय सिद्धांत
(B) मानव संबंध सिद्धांत
(C) व्यवस्था सिद्धांत
(D) नौकरशाही सिद्धांत

269. लोक निगम के लिए प्राधिकार का अंतिम स्रोत है:
(A) निदेशक मंडल
(B) सीईओ (CEO)
(C) विधायिका का वह अधिनियम जिसने इसे सृजित किया
(D) बाजार और उसके ग्राहक

270. राष्ट्र के प्रतीक के रूप में राष्ट्रपति की भूमिका उनकी किस भूमिका के अंतर्गत आती है?
(A) मुख्य कार्यपालिका
(B) सरकार के प्रमुख
(C) राज्य के प्रमुख (Head of State)
(D) कमांडर-इन-चीफ

271. कौन सा कथन 'अनौपचारिक संगठन' को सबसे अच्छी तरह परिभाषित करता है?

244. 'स्टाफ' एजेंसियों के विकास का एक प्रमुख कारण है:
(A) अधिक रोजगार सृजित करने की इच्छा।
(B) शासन की बढ़ती जटिलता।
(C) लाइन अधिकारियों की क्षमता में गिरावट।
(D) लाइन विभागों को दुर्बल करने का एक राजनीतिक निर्णय।

245. एक संगठन जो अत्यधिक केंद्रीकृत है, वह है जहाँ:
(A) अधिकांश निर्णय निचले स्तरों पर लिए जाते हैं।
(B) अधीनस्थों के पास पर्याप्त विवेक होता है।
(C) महत्वपूर्ण निर्णय लेने का अधिकार पदसोपान के शीर्ष पर बना रहता है।
(D) प्रबंधन के बहुत कम स्तर होते हैं।

246. कौन सा रूप उस कार्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है जिसे पक्षपातपूर्ण राजनीति से सुरक्षित रखने की आवश्यकता है?
(A) विभाग
(B) लोक निगम
(C) स्वतंत्र नियामक आयोग
(D) स्टाफ एजेंसी

247. 'पीटर सिद्धांत' (Peter Principle) किसकी आलोचना है?
(A) अनौपचारिक संगठन
(B) पदसोपानिक पदोन्नति प्रणाली
(C) विकेंद्रीकरण
(D) नियंत्रण का क्षेत्र

248. व्यवस्था दृष्टिकोण का शब्द 'एकसमानता' (equifinality) का अर्थ है:
(A) सभी प्रणालियों का एक ही अंतिम लक्ष्य होता है।
(B) एक व्यवस्था विभिन्न प्रारंभिक स्थितियों से एक ही अंतिम स्थिति तक पहुँच सकती है।
(C) सभी प्रणालियाँ अंततः एन्ट्रॉपी में क्षय हो जाती हैं।
(D) व्यवस्था का आउटपुट उसके इनपुट के बराबर होना चाहिए।

249. मुख्य कार्यपालिका के प्रशासनिक कार्य मुख्य रूप से किससे संबंधित हैं?
(A) विधि निर्माण
(B) वैदेशिक संबंध
(C) सरकारी तंत्र का प्रबंधन और देखरेख
(D) न्यायिक नियुक्तियां

250. 'विकास प्रशासन' का मूल विचार यह है कि प्रशासन किसके लिए एक साधन है?
(A) केवल सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए।
(B) राष्ट्रीय विकास को प्रोत्साहित करने और मार्गदर्शन करने के लिए।
(C) राज्य के लिए लाभ अर्जित करने के लिए।
(D) परिवर्तन और नवाचार का विरोध करने के लिए।

251. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन I: औपचारिक संगठन नियमों द्वारा परिभाषित होता है; अनौपचारिक संबंधों द्वारा।
कथन II: प्रभावी प्रबंधक अनौपचारिक संगठन की उपेक्षा करना सीखते हैं।
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
(D) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।

252. 'सोपानिक प्रक्रिया' और 'कार्यात्मक प्रक्रिया' किसके घटक हैं?
(A) पदसोपान
(B) संचार
(C) समन्वय
(D) अभिप्रेरणा

NODIA

253. कौन सा दृष्टिकोण चयन करने वाले व्यक्तिगत प्रशासक के मूल्यों और तर्कसंगतता में रुचि रखता है?
(A) पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण
(B) व्यवस्था दृष्टिकोण
(C) निर्णय-निर्माण दृष्टिकोण
(D) ऐतिहासिक दृष्टिकोण

254. 'स्पॉइल्स सिस्टम' (spoils system) किसके सिद्धांतों के विपरीत है?
(A) वेबर की योग्यता-आधारित नौकरशाही
(B) मानव संबंध सिद्धांत
(C) व्यवस्था सिद्धांत
(D) अनौपचारिक संगठन सिद्धांत

255. प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) का अस्तित्व किसका एक उदाहरण है?
(A) एक शक्तिशाली लाइन विभाग।
(B) मुख्य कार्यपालिका की सहायता करने वाली एक स्टाफ एजेंसी।
(C) एक लोक निगम।
(D) एक क्षेत्रीय इकाई।

256. लोक निगम के लिए एक प्रमुख दुविधा किसके बीच संतुलन स्थापित करना है?
(A) लाभ और हानि
(B) व्यावसायिक स्वायत्तता और सार्वजनिक उत्तरदायित्व
(C) केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण
(D) औपचारिक और अनौपचारिक नियम

257. नियंत्रण के संकीर्ण क्षेत्र वाले संगठन में होगा:
(A) एक सपाट (flat) संरचना
(B) एक लंबवत (tall) संरचना
(C) कोई संरचना नहीं
(D) एक विकेंद्रीकृत संरचना

उत्तर (व्याख्या सहित)

1. (B) लोक नीति का कार्यान्वयन और सरकारी गतिविधियों का प्रबंधन।
लोक प्रशासन एक विस्तृत विषय है जो मुख्य रूप से सरकारी नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन और सार्वजनिक कार्यक्रमों के प्रबंधन पर केंद्रित होता है। यह सरकारी गतिविधियों के सुचारु संचालन को सुनिश्चित करता है ताकि समाज के कल्याण हेतु निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। यह प्रशासनिक प्रक्रियाओं को राजनीतिक उद्देश्यों के साथ जोड़ता है, जिससे शासन में दक्षता, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित होता है।

2. (C) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
लोक प्रशासन में निर्णय-निर्माण दृष्टिकोण इस बात का गहराई से विश्लेषण करता है कि सरकारी अधिकारी उपलब्ध विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ का चयन किस प्रकार करते हैं। यद्यपि तर्कसंगत-व्यापक मॉडल एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, लेकिन यह प्रशासनिक निर्णयों की व्याख्या करने वाला एकमात्र वैध मार्ग नहीं है। हर्बर्ट साइमन जैसे विद्वानों ने सीमित तर्कसंगतता के सिद्धांत को प्रस्तुत किया है, जो मानवीय संज्ञानात्मक सीमाओं को स्वीकार करता है।

3. (C) फ्रेड डब्ल्यू. रिग्स
'प्रशासन की पारिस्थितिकी' की अवधारणा फ्रेड डब्ल्यू. रिग्स द्वारा विकसित की गई थी। उन्होंने तर्क दिया कि प्रशासनिक प्रणालियाँ अपने आसपास के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक वातावरण से प्रभावित होती हैं। रिग्स ने विकासशील देशों के प्रशासन का अध्ययन करने हेतु तुलनात्मक दृष्टिकोण अपनाया। उनके अनुसार, किसी भी प्रशासनिक तंत्र को उसके व्यापक परिवेश से अलग करके नहीं समझा जा सकता, क्योंकि बाहरी वातावरण ही उसे आकार देता है।

4. (D) पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण
पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण इस विचार पर आधारित है कि एक प्रशासनिक प्रणाली अपने बाहरी वातावरण के साथ निरंतर अंतःक्रिया करती है। यह समाज की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक शक्तियों के प्रशासनिक ढांचे पर पड़ने वाले प्रभावों का गहन विश्लेषण करता है। यह दृष्टिकोण बताता है कि बाहरी कारकों में होने वाले परिवर्तन प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सीधे प्रभावित करते हैं। प्रशासन को एक बंद इकाई के बजाय एक गतिशील प्रणाली माना जाता है।

5. (C) यथास्थिति-उन्मुख
विकास प्रशासन का मुख्य उद्देश्य समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाना और विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना है। यह प्रशासन की पुरानी परंपराओं के बजाय नवाचार और जन-केंद्रित कार्यों पर बल देता है। अतः यथास्थिति बनाए रखना इसकी विशेषता नहीं हो सकती, क्योंकि यह स्वभाव से प्रगतिशील और गतिशील होता है। यह प्रशासन नागरिकों की वास्तविक समस्याओं को हल करने और उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु सदैव प्रयासरत रहता है।

6. (A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
मैक्स वेबर का नौकरशाही सिद्धांत शास्त्रीय संगठन सिद्धांतों के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करता है। वेबर का मॉडल एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था का चित्रण करता है जहाँ स्पष्ट पदसोपान और लिखित नियमों का कड़ाई से पालन किया जाता है। यह संरचना कार्यों में उच्चतम दक्षता, पूर्वानुमान योग्यता और तार्किकता सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है। कार्यों के विशिष्ट विभाजन के माध्यम से यह एक निष्पक्ष प्रशासन प्रदान करता है।

7. (D) एक कर्मचारी को केवल एक ही वरिष्ठ से आदेश प्राप्त होने चाहिए।
आदेश की एकता का सिद्धांत किसी भी संगठन के कुशल संचालन के लिए अत्यंत आवश्यक माना जाता है। इसका अर्थ है कि प्रत्येक अधीनस्थ कर्मचारी को केवल एक ही उच्चाधिकारी से स्पष्ट निर्देश प्राप्त होने चाहिए। इससे संगठन में अनुशासन बना रहता है और कर्मचारियों के बीच कार्य को लेकर कोई भ्रम या विरोधाभास उत्पन्न नहीं होता। यह सिद्धांत उत्तरदायित्व के निर्धारण में सहायता करता है और आदेशों के दोहराव को रोकता है।

8. (A) नियंत्रण का क्षेत्र
नियंत्रण का क्षेत्र प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो उन अधीनस्थों की अधिकतम संख्या को निर्धारित करता है जिन्हें एक अधिकारी प्रभावी रूप से निर्देशित कर सकता है। यह सिद्धांत बताता है कि एक प्रबंधक की पर्यवेक्षण क्षमता सीमित होती है। यदि अधीनस्थों की संख्या बहुत अधिक हो जाए, तो समन्वय और नियंत्रण में गंभीर कठिनाई उत्पन्न होती है। उपयुक्त विस्तार संगठन की संरचना और अधीनस्थों की योग्यता पर निर्भर करता है।

9. (C) एक अनौपचारिक संगठन
एक अनौपचारिक संगठन वह है जो किसी औपचारिक ढांचे के भीतर मानवीय अंतःक्रियाओं और सामाजिक संबंधों के माध्यम से स्वतः विकसित होता है। यहाँ संचार और व्यवहार के नियम लिखित नहीं होते, बल्कि समूह के मानदंडों और व्यक्तिगत संबंधों पर आधारित होते हैं। यह संगठन कर्मचारियों की मनोवैज्ञानिक और सामाजिक आवश्यकताओं को पूर्ण करता है। यह कार्यस्थल पर सूचनाओं के तीव्र आदान-प्रदान और सामूहिक पहचान विकसित करने में सहायक होता है।

Downloaded from www.pdf.tube

(A) व्यक्तिगत संबंधों का एक नेटवर्क जिसकी आवश्यकता औपचारिक संगठन द्वारा नहीं होती है।
(B) संगठन की संरचना का आधिकारिक प्रारूप।
(C) किसी विशिष्ट परियोजना के लिए सृजित एक अस्थायी कार्य बल।
(D) लोक निगम का दूसरा नाम।

272. केंद्रीकरण का एक प्रमुख लाभ है:
(A) निचले स्तरों पर पहल को बढ़ावा देना।
(B) नियमित स्थानीय विषयों के लिए त्वरित निर्णय लेना।
(C) नीति और कार्यवाही की एकरूपता सुनिश्चित करना।
(D) शीर्ष प्रबंधन के कार्यभार को कम करना।

273. सूची I को सूची II के साथ सुमेलित कीजिए:
सूची I (संगठनात्मक अवधारणा):
P. वैज्ञानिक प्रबंधन
Q. मानव संबंध
R. नौकरशाही
S. व्यवस्था दृष्टिकोण।
सूची II (प्राथमिक ध्यान):
1. सामाजिक कारक
2. कार्य कुशलता
3. संगठन-वातावरण अंतःक्रिया
4. तर्कसंगतता और नियम।
(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-2, Q-1, R-4, S-3
(C) P-2, Q-4, R-1, S-3
(D) P-4, Q-1, R-2, S-3

274. 'प्रशासनिक मानव' की अवधारणा की तुलना उस 'आर्थिक मानव' से की जाती है जो:
(A) न्यूनतम करता है
(B) समझौता करता है
(C) अधिकतम करता है
(D) उपेक्षा करता है

275. सूचना प्रवाह को प्रबंधित करने के लिए 'चीफ ऑफ स्टाफ' की नियुक्ति किसका उदाहरण है?
(A) लाइन पद
(B) स्टाफ पद
(C) बहुल कार्यपालिका
(D) विभागीय प्रमुख

276. तुलनात्मक लोक प्रशासन में 'पारिस्थितिकीय भ्रम' (ecological fallacy) क्या होगा?
(A) यह मान लेना कि प्रशासनिक प्रथाएं वातावरण द्वारा निर्धारित होती हैं।
(B) यह मान लेना कि एक संदर्भ में कार्य करने वाली प्रथा दूसरे संदर्भ में भी कार्य करेगी।
(C) प्रशासन के स्थान पर वातावरण का अध्ययन करना।
(D) वातावरण पर प्रशासन के प्रभाव की उपेक्षा करना।

277. संसदीय प्रणाली में 'मंत्रिमंडल' किसका उदाहरण है?
(A) एक बहुल कार्यपालिका जो राजनीतिक और प्रशासनिक नेतृत्व को जोड़ती है।
(B) एक विशुद्ध रूप से नाममात्र की कार्यकारी संस्था।
(C) एक स्वतंत्र न्यायिक परिषद।
(D) एक स्टाफ एजेंसी।

278. नियंत्रण का एक विस्तृत क्षेत्र सर्वाधिक तब व्यवहार्य होता है जब:
(A) कार्य जटिल और विविध हों।
(B) अधीनस्थ अनुभवहीन हों।
(C) कार्य नियमित हों और अधीनस्थ प्रशिक्षित हों।
(D) संगठन अत्यधिक केंद्रीकृत हो।

279. सरकार के प्राथमिक मंत्रालयों के लिए उपयोग किए जाने वाले संगठन का रूप है:
(A) विभाग
(B) लोक निगम
(C) परिषद
(D) आयोग

280. विकास प्रशासन की एक प्रमुख आलोचना रही है:
(A) महत्वाकांक्षा की कमी।
(B) भागीदारी पर अत्यधिक बल।
(C) सत्तावाद की ओर झुकाव।
(D) योजना बनाने में असमर्थता।

281. लाइन और स्टाफ अधिकारी के बीच मुख्य अंतर यह है कि लाइन अधिकारी के पास होता है:
(A) अधिक ज्ञान
(B) अधिक अनुभव
(C) आदेश देने का अधिकार
(D) उच्च वेतन

282. 'गैंगप्लैंक' (gangplank) किसकी सीमाओं से निपटने के लिए एक तंत्र है?
(A) नियंत्रण का क्षेत्र
(B) सोपानिक श्रृंखला (पदसोपान)
(C) आदेश की एकता
(D) श्रम विभाजन

283. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन I: त्वरित कार्यकारी कार्यवाही के लिए एक परिषद प्रभावी होती है।
कथन II: एक परिषद विचार-विमर्श को बढ़ावा देती है लेकिन निर्णय लेने में विलंब कर सकती है।
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
(D) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।

NODIA

284. 'प्रशासकीय राज्य' (administrative state) के विकास ने किस पर ध्यान केंद्रित किया?
(A) सम्राट
(B) न्यायपालिका
(C) मुख्य कार्यपालिका
(D) विधायिका

285. निर्णय लेने में, 'ह्यूरिस्टिक्स' (heuristics) क्या हैं?
(A) जटिल गणितीय मॉडल।
(B) निर्णय लेने को सरल बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानसिक संक्षिप्त मार्ग।
(C) सभी संभव विकल्पों का समूह।
(D) निर्णय लेने वाले के मूल्य।

286. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है:
अभिकथन (A): लोक प्रशासन के अध्ययन में महत्वपूर्ण विकास हुआ है।
कारण (R): प्रारंभिक वैज्ञानिक सिद्धांतों के स्थान पर व्यवहारवादी और पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण आए।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

287. कौन सा सिद्धांत इसमें रुचि रखता है कि सामाजिक गतिशीलता उत्पादकता को कैसे प्रभावित करती है?
(A) नौकरशाही सिद्धांत
(B) वैज्ञानिक प्रबंधन
(C) मानव संबंध सिद्धांत
(D) आकस्मिकता सिद्धांत

288. 'सपाट' (flat) संगठनात्मक संरचना किसका पर्याय है?
(A) लंबवत पदसोपान (Tall hierarchy)
(B) नियंत्रण का संकीर्ण क्षेत्र
(C) नियंत्रण का विस्तृत क्षेत्र
(D) केंद्रीकरण का उच्च स्तर

289. संगठन का कौन सा रूप 'निगमनात्मक व्यक्तित्व' की विशेषता रखता है और वाद प्रस्तुत कर सकता है या उस पर वाद किया जा सकता है?
(A) विभाग
(B) स्टाफ एजेंसी
(C) लोक निगम
(D) अनौपचारिक समूह

290. यह अवधारणा कि अधिकार अधीनस्थ की इसे स्वीकार करने की इच्छा से उत्पन्न होता है:
(A) ऊपर से नीचे का सिद्धांत
(B) अधिकार का स्वीकृति सिद्धांत
(C) करिश्माई सिद्धांत
(D) कानूनी-तर्कसंगत सिद्धांत

291. लाइन-स्टाफ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. लाइन एजेंसियां प्राथमिक लक्ष्यों को प्राप्त करती हैं।
2. स्टाफ एजेंसियां सहायता प्रदान करती हैं।
3. यह अंतर कभी-कभी धुंधला हो सकता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3

292. 'एग्रेरिया' (agraria) और 'इंडस्ट्रिया' (industria) मॉडल किसके पूर्ववर्ती थे?
(A) निर्णय-निर्माण मॉडल
(B) व्यवस्था मॉडल
(C) प्रिज्माटिक-साला मॉडल
(D) नौकरशाही मॉडल

293. लोक निगम पर अंतिम नियंत्रण किसका होता है?
(A) बाजार
(B) सीईओ (CEO)
(C) संसद या विधायिका
(D) कर्मचारी संघ

294. "प्रशासन के प्रत्येक सिद्धांत के लिए एक प्रति-सिद्धांत है।" यह किसके द्वारा कहा गया था?
(A) हेनरी फेयोल
(B) हर्बर्ट साइमन
(C) वुड्रो विल्सन
(D) एफ.डब्ल्यू. टेलर

295. सूची I को सूची II के साथ सुमेलित कीजिए:
सूची I (संगठनात्मक विकृति):
P. लालफीताशाही
Q. लक्ष्य विस्थापन
R. पीटर सिद्धांत
S. पार्किंसंस नियम।
सूची II (विवरण):
1. समय भरने के लिए कार्य का विस्तार होता है
2. नियम ही साध्य बन जाते हैं
3. अक्षमता तक पदोन्नति
4. जटिल प्रक्रियाओं का अत्यधिक अनुपालन।
(A) P-4, Q-2, R-3, S-1
(B) P-2, Q-4, R-1, S-3
(C) P-4, Q-3, R-2, S-1
(D) P-1, Q-2, R-3, S-4

Click Here to Buy book on Amazon

296. 'कोलेजियल' (collegial) कार्यपालिका किसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त है?
(A) तीव्र कार्यवाही और गोपनीयता
(B) विचार-विमर्श और प्रतिनिधित्व
(C) कमान का एक एकल बिंदु
(D) सैन्य-शैली का नेतृत्व

297. व्यवस्था दृष्टिकोण (Systems Approach) में 'नकारात्मक फीडबैक' का अर्थ है:
(A) प्रदर्शन की आलोचना।
(B) यह इंगित करने वाली सूचना कि व्यवस्था को सुधार की आवश्यकता है।
(C) व्यवस्था के क्षय होने की प्रवृत्ति।
(D) व्यवस्था के प्रतिकूल आउटपुट।

298. निम्नलिखित में से कौन विकास प्रशासन का प्रमुख प्रतिपादक है?
(A) मैक्स वेबर
(B) एडवर्ड वीडनर
(C) वुड्रो विल्सन
(D) एल्टन मेयो

299. यदि एक सीईओ 400 कर्मचारियों के लिए 6 प्रत्यक्ष अधीनस्थों का प्रबंधन करता है, तो संगठन में क्या है?
(A) नियंत्रण का क्षेत्र
(B) एक पदसोपान (Hierarchy)
(C) एक मिशन वक्तव्य
(D) एक औपचारिक संरचना

300. 'आदेश की एकता' के सिद्धांत का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?
(A) विशेषीकरण को प्रोत्साहित करना।
(B) भ्रम और विरोधाभासी आदेशों से बचना।
(C) नियंत्रण के क्षेत्र को विस्तृत करना।
(D) विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना।

www.nodia.in

NODIA

नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

233. एक जटिल कार्य को छोटे, सरल कार्यों में विभक्त करने की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है?
(A) श्रम विभाजन या विशेषीकरण
(B) पदसोपान
(C) नियंत्रण का क्षेत्र
(D) आदेश की एकता

234. 'गैंगप्लैंक' (Gangplank) अवधारणा का उद्देश्य क्या था?
(A) कठोर पदसोपानिक संचार को सुदृढ़ करना।
(B) एक ही स्तर पर कर्मचारियों के बीच तीव्र संचार की सुविधा प्रदान करना।
(C) अधीनस्थों को उनके तत्काल वरिष्ठों को बायपास करने की अनुमति देना।
(D) लिखित संचार की आवश्यकता को समाप्त करना।

235. "सीमित तर्कसंगतता" (bounded rationality) की अवधारणा किसके मॉडल के विकल्प के रूप में प्रस्तुत की गई थी?
(A) सामाजिक मानव (Social Man)
(B) राजनीतिक मानव (Political Man)
(C) आर्थिक मानव (Economic Man)
(D) प्रशासनिक मानव (Administrative Man)

236. 'हाथोर्न प्रभाव' (Hawthorne effect) किसके कारण विषयों के व्यवहार में परिवर्तन को संदर्भित करता है?
(A) भौतिक स्थितियों में परिवर्तन।
(B) प्रस्तुत वित्तीय प्रोत्साहन।
(C) उनके पर्यवेक्षण के प्रति जागरूकता।
(D) कार्य की कठिनाई।

237. 'बहुल कार्यपालिका' (plural executive) रखने का एक प्रमुख उद्देश्य है:
(A) त्वरित और निर्णायक कार्यवाही सुनिश्चित करना।
(B) एक व्यक्ति में शक्ति केंद्रित करना।
(C) विचार-विमर्श को बढ़ावा देना और शक्ति का प्रसार करना।
(D) उत्तरदायित्व की प्रक्रिया को सरल बनाना।

238. संगठन के सिद्धांतों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. शास्त्रीय सिद्धांत औपचारिक संरचना पर केंद्रित था।
2. मानव संबंध सिद्धांत ने सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर बल दिया।
3. व्यवस्था सिद्धांत संगठन को एक खुली व्यवस्था के रूप में देखता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3

239. सरकारी सेवा प्रदान करने के लिए संगठन का सबसे बुनियादी रूप है:
(A) लोक निगम
(B) परिषद
(C) विभाग
(D) अनौपचारिक समूह

240. रिग्स के पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण में 'पारिस्थितिकी' किसे संदर्भित करती है?
(A) भौतिक वातावरण और पर्यावरण अनुकूल नीतियां।
(B) प्रशासन और उसके सामाजिक परिवेश के बीच परस्पर संबंध।
(C) किसी सरकारी एजेंसी का आंतरिक कार्यालय वातावरण।
(D) किसी देश के भीतर जैविक तंत्र।

241. संगठन के एक सिद्धांत के रूप में 'निर्देशन की एकता' (Unity of Direction) का अर्थ है:
(A) एक अधीनस्थ का एक ही उच्चाधिकारी होना चाहिए।
(B) एक ही उद्देश्य वाली सभी गतिविधियों का एक प्रमुख और एक योजना होनी चाहिए।
(C) अधिकार का विकेंद्रीकरण होना चाहिए।
(D) नियंत्रण का क्षेत्र संकीर्ण होना चाहिए।

242. सूची I को सूची II के साथ सुमेलित कीजिए:
सूची I (मुख्य कार्यपालिका प्रकार):
P. एकल अध्यक्षीय
Q. एकल संसदीय (वास्तविक)
R. नाममात्र संसदीय (राज्य का प्रमुख)
S. बहुल कॉलेजियम।
सूची II (देश का उदाहरण):
1. भारत के राष्ट्रपति
2. स्विट्जरलैंड की संघीय परिषद
3. संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति
4. यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री।
(A) P-3, Q-4, R-1, S-2
(B) P-3, Q-1, R-4, S-2
(C) P-2, Q-4, R-1, S-3
(D) P-4, Q-3, R-2, S-1

243. व्यवहारवादी आंदोलन का प्राथमिक योगदान किस पर इसका ध्यान केंद्रित करना था?
(A) औपचारिक विधिक संरचनाएं।
(B) संगठनों के भीतर व्यक्तियों का वास्तविक व्यवहार।
(C) प्रबंधन के सार्वभौमिक सिद्धांत।
(D) प्रशासनिक संस्थानों का इतिहास।

Downloaded from www.pdf.tube

10. (B) P-4, Q-1, R-2, S-3
सरकारी संगठन के विभिन्न रूप विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं। विभाग शासन की पारंपरिक प्रशासनिक इकाइयाँ होते हैं, जबकि लोक निगम व्यावसायिक सिद्धांतों और सार्वजनिक उत्तरदायित्व का समन्वय करते हैं। परिषदें सामूहिक निर्णय लेने या नीतिगत परामर्श प्रदान करने के लिए गठित की जाती हैं। इसके विपरीत, अनौपचारिक संगठन सामाजिक संबंधों पर आधारित होते हैं। ये सभी रूप मिलकर प्रशासनिक तंत्र को व्यापकता और क्रियाशीलता प्रदान करते हैं।

11. (D) संगठन के प्राथमिक उद्देश्यों को पूर्ण करना।
लाइन और स्टाफ संगठन में लाइन इकाइयाँ सीधे उन मुख्य कार्यों को निष्पादित करती हैं जिनके लिए संगठन की स्थापना की गई है। ये इकाइयाँ आदेश देने का अधिकार रखती हैं और नीतिगत लक्ष्यों की प्रत्यक्ष प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इनके बिना संगठन का अस्तित्व संभव नहीं है क्योंकि ये प्राथमिक सेवाओं के वितरण से जुड़ी होती हैं। स्टाफ इकाइयाँ केवल परामर्श और सहायता प्रदान करती हैं, जबकि वास्तविक कार्यान्वयन लाइन का दायित्व है।

12. (B) एकल और अध्यक्षीय कार्यपालिका
संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति एकल और अध्यक्षीय कार्यपालिका का एक प्रमुख उदाहरण है। अध्यक्षीय प्रणाली में, कार्यपालिका का प्रमुख सीधे तौर पर राज्य और सरकार दोनों का नेतृत्व करता है। वह विधायिका से स्वतंत्र होता है और उसका कार्यकाल निश्चित होता है। यहाँ कार्यकारी शक्तियाँ एक ही व्यक्ति में निहित होती हैं, जिससे त्वरित निर्णय लेने और नीतियों के दृढ़ कार्यान्वयन में सहायता मिलती है। यह व्यवस्था शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित है।

13. (C) परस्पर संबंधित और परस्पर निर्भर भागों का एक समूह जो समग्र रूप से कार्य करता है।
व्यवस्था दृष्टिकोण संगठन को एक एकीकृत इकाई के रूप में देखता है जहाँ विभिन्न विभाग और इकाइयाँ परस्पर संबंधित होती हैं। यह दृष्टिकोण मानता है कि संगठन के एक भाग में होने वाला परिवर्तन अन्य सभी भागों को प्रभावित करता है। संगठन अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बाहरी वातावरण से संसाधन प्राप्त करता है और उसे परिणाम में बदलता है। यह दृष्टिकोण समन्वय, अनुकूलन और संपूर्ण संगठन की गतिशीलता को समझने में सहायक है।

14. (A) केवल 1 और 2
हर्बर्ट साइमन ने सीमित तर्कसंगतता की अवधारणा दी, जो मानती है कि निर्णय लेने वाले अपनी मानसिक सीमाओं और अपूर्ण सूचनाओं के भीतर कार्य करते हैं। संतोषप्रद मॉडल के अनुसार, व्यक्ति सर्वोत्तम विकल्प के बजाय प्रथम संतोषजनक विकल्प को चुनता है। साइमन ने यह तर्क दिया कि प्रशासनिक निर्णयों में तथ्यों और मूल्यों दोनों की भूमिका होती है। कथन 3 गलत है क्योंकि उन्होंने तथ्यों और मूल्यों के बीच अंतर स्पष्ट किया था।

15. (A) औपचारिक अधिकार संरचना के साथ सचेत रूप से समन्वित गतिविधियों की एक प्रणाली।
औपचारिक संगठन की सबसे विशिष्ट विशेषता इसकी सचेत रूप से निर्मित संरचना और समन्वय है। इसमें प्रत्येक कर्मचारी की भूमिका, अधिकार और उत्तरदायित्व लिखित नियमों द्वारा स्पष्ट रूप से परिभाषित होते हैं। यह संगठन विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए तार्किक रूप से बनाया जाता है। इसमें आदेश की श्रृंखला और संचार के औपचारिक चैनल होते हैं, जो संस्थागत मानदंडों के अनुसार संचालित होते हैं। यह संगठन में स्थिरता और दक्षता सुनिश्चित करता है।

16. (B) एक संक्रमणकालीन समाज है जो पारंपरिक और आधुनिक दोनों विशेषताओं को प्रदर्शित करता है।
फ्रेड रिग्स के अनुसार, प्रिज्मीय समाज एक ऐसा समाज है जो पारंपरिक अवस्था से आधुनिक अवस्था की ओर बढ़ रहा है। ऐसे समाजों में आधुनिक प्रशासनिक संरचनाएँ तो मौजूद होती हैं, लेकिन वे पुराने सामाजिक मूल्यों से गहराई से प्रभावित रहती हैं। यहाँ औपचारिकतावाद और अतिव्यापन जैसे लक्षण पाए जाते हैं। यह मॉडल विशेष रूप से विकासशील देशों की प्रशासनिक व्यवस्था और सामाजिक वास्तविकता को समझने के लिए अत्यंत उपयोगी और प्रासंगिक माना जाता है।

17. (B) मुख्य कार्यपालिका के कार्य प्रकृति में विशुद्ध रूप से प्रशासनिक होते हैं।
मुख्य कार्यपालिका की भूमिका केवल प्रशासनिक कार्यों तक सीमित नहीं होती है। वह नीति निर्धारण, विधायी नेतृत्व और राजनीतिक निर्णयों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मुख्य कार्यपालिका बजट तैयार करती है, प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति करती है और अंतरराष्ट्रीय संबंधों का संचालन करती है। इसके अतिरिक्त, वह सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर के रूप में भी कार्य करती है। अतः यह कहना गलत है कि उसके कार्य केवल प्रशासनिक प्रकृति के होते हैं।

18. (A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
विकेंद्रीकरण एक प्रशासनिक प्रक्रिया है जिसमें केंद्र सरकार अपने निर्णय लेने के अधिकार और उत्तरदायित्व निचले स्तरों को हस्तांतरित करती है। यह व्यवस्था शासन को जनता के अधिक निकट लाती है, जिससे स्थानीय समस्याओं का समाधान तीव्रता से संभव होता है। इससे निचले स्तर के अधिकारियों का मनोबल बढ़ता है और प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि होती है। स्थानीय आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशीलता विकेंद्रीकरण का प्रमुख लाभ है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करता है।

19. (C) पदसोपान
स्केलर चेन या सोपानिक श्रृंखला की अवधारणा संगठन के पदसोपान सिद्धांत से निकटता से जुड़ी हुई है। यह ऊपर से नीचे तक अधिकार की एक अटूट रेखा को दर्शाती है, जो वरिष्ठों और अधीनस्थों के बीच संचार का मार्ग प्रशस्त करती है। इसके माध्यम से आदेशों का प्रवाह और उत्तरदायित्व का निर्धारण सुनिश्चित किया जाता है। यह सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि संगठन में प्रत्येक कर्मचारी को स्पष्ट रूप से पता हो कि वह किसके प्रति उत्तरदायी है।

NODIA

20. (D) नए स्वतंत्र और विकासशील देश।
विकास प्रशासन का उदय द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विशेष रूप से नए स्वतंत्र राष्ट्रों की समस्याओं के समाधान हेतु हुआ। इन देशों को गरीबी, निरक्षरता और आर्थिक पिछड़ेपन जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। पारंपरिक प्रशासन जहाँ केवल विधि-व्यवस्था बनाए रखने तक सीमित था, वहीं विकास प्रशासन ने सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन लाने और राष्ट्र निर्माण पर बल दिया। यह दृष्टिकोण लोक प्रशासन को अधिक गतिशील, प्रगतिशील और परिणाम-उन्मुख बनाने की दिशा में बढ़ा कदम था।

21. (C) लोक निगम
लोक निगम एक ऐसा संगठनात्मक रूप है जिसे संसद के विशेष अधिनियम द्वारा बनाया जाता है। इसकी अपनी कानूनी पहचान होती है और यह व्यावसायिक सिद्धांतों पर कार्य करता है। लोक निगमों को वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त होती है और उनका अपना स्वतंत्र बजट होता है। यद्यपि वे नीतिगत विषयों पर सरकार और संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं, लेकिन उन्हें दैनिक प्रबंधन में पर्याप्त स्वतंत्रता प्राप्त होती है। यह सार्वजनिक सेवा और व्यावसायिक दक्षता का मिश्रण है।

22. (A) 3, 2, 1, 4
लोक प्रशासन के सिद्धांतों का विकास एक व्यवस्थित क्रम में हुआ है। सबसे पहले 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में वैज्ञानिक प्रबंधन का उदय हुआ। इसके बाद 1930 के दशक में एल्टन मेयो द्वारा मानव संबंध सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। 1950 के दशक में व्यवस्था दृष्टिकोण ने संगठन को एक समग्र इकाई के रूप में देखा। अंततः 1960 के दशक में विकास प्रशासन की अवधारणा ने विकासशील देशों की विशिष्ट आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए जन्म लिया।

23. (D) हर्बर्ट ए. साइमन
निर्णय लेने की प्रक्रिया में तथ्य-मूल्य द्विभाजन की अवधारणा हर्बर्ट साइमन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। साइमन ने तर्क दिया कि प्रशासनिक निर्णयों में दो प्रकार के आधार होते हैं: तथ्य, जिन्हें अनुभवजन्य रूप से जाँचा जा सकता है, और मूल्य, जो व्यक्तिगत पसंद या नैतिक मानदंडों पर आधारित होते हैं। उन्होंने प्रशासकों को तथ्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी ताकि निर्णय तार्किक हो सकें। यह विचार आधुनिक व्यवहारवादी विश्लेषण का आधार बना।

24. (A) चेस्टर बर्नार्ड - वैज्ञानिक प्रबंधन
चेस्टर बर्नार्ड वैज्ञानिक प्रबंधन से नहीं, बल्कि सामाजिक व्यवस्था सिद्धांत और संगठन में मानवीय सहयोग की अवधारणा से जुड़े हैं। वैज्ञानिक प्रबंधन के मुख्य प्रतिपादक फ्रेडरिक विंसलो टेलर हैं। अन्य विकल्पों में फ्रेड रिग्स का पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण, हर्बर्ट साइमन का निर्णय-निर्माण दृष्टिकोण और मैक्स वेबर का नौकरशाही सिद्धांत सही सुमेलित हैं। बर्नार्ड ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'द फंक्शन्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव' में कार्यपालिका की भूमिका और संचार व्यवस्था पर विचार प्रस्तुत किए थे।

25. (C) परिचालन इकाइयों को प्रत्यक्ष आदेश जारी करना।
एक स्टाफ एजेंसी का मुख्य कार्य मुख्य कार्यपालिका को विशेषज्ञ सलाह, अनुसंधान और योजना बनाने में सहायता प्रदान करना है। इसके पास लाइन इकाइयों को सीधे आदेश देने या उनके कार्यों को नियंत्रित करने का कोई कार्यकारी अधिकार नहीं होता है। स्टाफ एजेंसियाँ केवल सूचनाओं का विश्लेषण करती हैं और भविष्य की नीतियों के लिए रूपरेखा तैयार करती हैं। उनका प्रभाव उनके ज्ञान और परामर्श की गुणवत्ता पर निर्भर करता है, न कि प्रत्यक्ष प्रशासनिक शक्ति के प्रयोग पर।

26. (A) संगठन के उच्च स्तरों पर निर्णय लेने के अधिकार का संकेंद्रण।
केंद्रीकरण का अर्थ है कि संगठन के भीतर सभी महत्वपूर्ण निर्णय लेने की शक्ति शीर्ष नेतृत्व या केंद्रीय अधिकारियों के पास सुरक्षित रहती है। इस प्रणाली में निचले स्तर के कर्मचारियों को बहुत कम स्वायत्तता प्राप्त होती है और उन्हें केवल ऊपर से प्राप्त आदेशों का पालन करना होता है। केंद्रीकरण नीतियों में एकरूपता और नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए अपनाया जाता है। यह छोटे संगठनों या संकट की स्थितियों में त्वरित निर्णय लेने के लिए प्रभावी होता है।

27. (A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
हाथोर्न प्रयोग लोक प्रशासन के इतिहास में क्रांतिकारी थे क्योंकि उन्होंने उत्पादकता के लिए भौतिक स्थितियों के बजाय सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारकों के महत्व को सिद्ध किया। इन अध्ययनों के दौरान यह पाया गया कि जब श्रमिकों को लगता है कि उन पर ध्यान दिया जा रहा है, तो उनका प्रदर्शन स्वतः सुधर जाता है। इन प्रयोगों ने ही मानव संबंध विचारधारा की नींव रखी और श्रमिकों को मशीन के पुर्जों के स्थान पर सजीव मनुष्य माना।

28. (C) व्यवस्था दृष्टिकोण
व्यवस्था दृष्टिकोण के अंतर्गत संगठन को एक ऐसी इकाई माना जाता है जो इनपुट, रूपांतरण, परिणाम और प्रतिपुष्टि के चक्र पर आधारित होती है। यहाँ इनपुट का अर्थ वातावरण से प्राप्त संसाधन है और परिणाम अंतिम उपलब्धि है। प्रतिपुष्टि तंत्र यह सुनिश्चित करता है कि व्यवस्था अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ रही है और आवश्यक समायोजन कर रही है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया संगठन की स्थिरता और बाहरी वातावरण के साथ संतुलन बनाए रखती है।

29. (D) अधिक वित्तीय लचीलापन।
लोक निगमों को सरकारी विभागों की तुलना में अधिक वित्तीय और परिचालन स्वायत्तता प्रदान की जाती है। उनके पास अपना स्वतंत्र बजट होता है और वे अपनी आय का उपयोग स्वयं के विस्तार और विकास के लिए कर सकते हैं। वे कठोर बजटीय नियंत्रणों और वार्षिक सरकारी लेखा परीक्षा की जटिलताओं से अपेक्षाकृत मुक्त होते हैं। यह लचीलापन उन्हें व्यावसायिक चुनौतियों का सामना करने और बाजार की बदलती स्थितियों के अनुसार त्वरित वित्तीय निर्णय लेने में सक्षम बनाता है।

Click Here to Buy book on Amazon

30. (B) राज्य के प्रमुख की भूमिका
मुख्य कार्यपालिका जब राज्य के प्रमुख के रूप में कार्य करती है, तो वह राष्ट्र की एकता और गौरव का प्रतीक होती है। इस भूमिका में राजनीतिक या प्रशासनिक कार्यों के बजाय औपचारिक और प्रतीकात्मक कर्तव्यों की प्रधानता होती है। इसमें विदेशी राजदूतों का स्वागत करना और राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करना जैसे कार्य सम्मिलित हैं। संसदीय प्रणालियों में यह भूमिका प्रायः नाममात्र की कार्यपालिका द्वारा निभाई जाती है, जबकि अध्यक्षीय प्रणालियों में यह वास्तविक कार्यपालिका में निहित होती है।

31. (A) वुड्रो विल्सन
वुड्रो विल्सन को लोक प्रशासन के जनक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने 1887 में अपने प्रसिद्ध निबंध 'द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन' में राजनीति और प्रशासन के बीच स्पष्ट विभाजन की वकालत की थी। उनका मानना था कि प्रशासन एक व्यावसायिक क्षेत्र है जो राजनीति के उतार-चढ़ाव से मुक्त होना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि नीति निर्धारण राजनीति का कार्य है, जबकि नीतियों का कुशल कार्यान्वयन प्रशासन का कार्य है। इस विचार ने लोक प्रशासन को स्वतंत्र विषय बनाया।

32. (B) आधुनिक मानदंडों और पारंपरिक सामाजिक मूल्यों की एक साथ उपस्थिति।
फ्रेड रिग्स के प्रिज्मीय समाज में विषमता का तात्पर्य एक ऐसी स्थिति से है जहाँ विरोधाभासी तत्व एक साथ विद्यमान रहते हैं। यहाँ पश्चिमी देशों की आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था और पुरानी पारंपरिक प्रथाएँ एक ही समय में कार्य करती हैं। उदाहरण के लिए, एक तरफ उच्च तकनीक वाले कार्यालय हो सकते हैं, तो दूसरी तरफ भर्ती में भाई-भतीजावाद प्रभावी हो सकता है। यह लक्षण विशेष रूप से विकासशील राष्ट्रों की सामाजिक और प्रशासनिक संरचना को गहराई से परिभाषित करता है।

33. (A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
किसी भी औपचारिक संगठन के भीतर अनौपचारिक संगठनों का बनना एक स्वाभाविक मानवीय प्रक्रिया है। चूँकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए वह कार्यस्थल पर केवल निर्धारित नियमों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि अन्य कर्मचारियों के साथ व्यक्तिगत संबंध भी बनाता है। ये समूह साझा हितों या मित्रता पर आधारित होते हैं। वे आधिकारिक संगठनात्मक चार्ट का हिस्सा नहीं होते, लेकिन संगठन के भीतर सूचनाओं के प्रवाह और कार्य संस्कृति को काफी हद तक प्रभावित करते हैं।

34. (C) एक सामूहिक निकाय द्वारा विचार-विमर्श, परामर्श या विनियमन की आवश्यकता वाले कार्य।
परिषद का उपयोग प्रायः उन प्रशासनिक कार्यों के लिए किया जाता है जहाँ विशेषज्ञता और विभिन्न दृष्टिकोणों के बीच समन्वय की आवश्यकता होती है। यह एक सामूहिक निकाय होता है जहाँ किसी एक व्यक्ति के निर्णय के बजाय आपसी सहमति और चर्चा को महत्व दिया जाता है। इस प्रकार के संगठनों का गठन नीति निर्माण या सलाहकार कार्यों के लिए किया जाता है। परिषदें यह सुनिश्चित करती हैं कि महत्वपूर्ण निर्णय व्यापक विचार-विमर्श के बाद ही लिए जाएँ, जिससे लोकतंत्र को बढ़ावा मिलता है।

35. (B) पदसोपान
'गैंगप्लैंक' या सीधा संचार की अवधारणा का उपयोग पदसोपान के कठोर नियमों को दरकिनार करने के लिए किया जाता है। पदसोपान सिद्धांत के अनुसार, संचार सदैव आदेश की श्रृंखला का पालन करते हुए होना चाहिए। लेकिन कभी-कभी तीव्र निर्णय लेने के लिए दो अलग-अलग शाखाओं के कर्मचारी सीधे संवाद करते हैं, जो औपचारिक पदसोपान का उल्लंघन है। हेनरी फेयोल ने आपात स्थितियों में समय की बचत के लिए इस तकनीक के प्रयोग की अनुमति दी थी ताकि कार्य में विलंब न हो।

36. (B) केवल 2 और 3
शास्त्रीय संगठन सिद्धांत मुख्य रूप से औपचारिक संरचना, कार्य विभाजन और दक्षता के सार्वभौमिक नियमों पर बल देते हैं। ये सिद्धांत संगठनों को एक मशीन की तरह देखते हैं जहाँ श्रमिक केवल उत्पादकता बढ़ाने के साधन होते हैं। इसमें मानवीय भावनाओं और अनौपचारिक संबंधों की उपेक्षा की जाती है। कथन 1 गलत है क्योंकि अनौपचारिक संरचनाओं पर बल देना मानव संबंध सिद्धांत की विशेषता है। शास्त्रीय विचारक मानते थे कि प्रबंधन के निश्चित सिद्धांत हर प्रकार के संगठन पर लागू होते हैं।

37. (D) नियमित होते हैं और एक निश्चित, स्थापित प्रक्रिया का अनुकरण करते हैं।
हर्बर्ट साइमन के अनुसार, नियोजित निर्णय वे होते हैं जो बार-बार होने वाली समस्याओं के समाधान के लिए लिए जाते हैं। इनके लिए संगठन में पहले से ही नियम, प्रक्रियाएँ और मानक निर्धारित होते हैं, इसलिए हर बार नए सिरे से सोचने की आवश्यकता नहीं होती। ये निर्णय प्रायः निचले स्तर के प्रबंधकों द्वारा लिए जाते हैं। नियमितता और संरचना इनकी मुख्य विशेषता है, जिससे प्रशासनिक कार्यों में स्थिरता बनी रहती है और संसाधनों का कुशल उपयोग सुनिश्चित होता है।

38. (A) सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन लाना।
विकास प्रशासन का प्राथमिक लक्ष्य समाज के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक बुनियादी ढाँचा तैयार करना और प्रगतिशील परिवर्तन लाना है। यह केवल पारंपरिक प्रशासनिक कार्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि गरीबी उन्मूलन और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए समर्पित है। यह दृष्टिकोण राष्ट्र निर्माण और लोक कल्याण के उद्देश्यों को सर्वोपरि मानता है। इसके माध्यम से प्रशासन को अधिक सक्रिय और नागरिक-उन्मुख बनाकर विकासशील देशों की विशिष्ट समस्याओं का प्रभावी समाधान किया जाता है।

39. (B) थ्रूपुट
व्यवस्था दृष्टिकोण के अंतर्गत, थ्रूपुट वह महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें संगठन बाहरी वातावरण से प्राप्त इनपुट या संसाधनों का रूपांतरण करता है। इस प्रक्रिया में कच्चा माल, सूचना और ऊर्जा संगठनात्मक गतिविधियों के माध्यम से परिणाम

Downloaded from www.pdf.tube

व्यवहारवादी दृष्टिकोण और हर्बर्ट साइमन के कार्यों से संबंधित है। शास्त्रीय विचारक मानते थे कि संगठन की संरचना को इन नियमों के अनुसार व्यवस्थित करके अधिकतम उत्पादकता प्राप्त की जा सकती है।

58. (D) नवीन, असंरचित और जटिल होती हैं।
अनियोजित निर्णय वे होते हैं जो किसी ऐसी समस्या के उत्पन्न होने पर लिए जाते हैं जिसके लिए पहले से कोई स्थापित नियम या प्रक्रिया उपलब्ध नहीं होती। ये स्थितियाँ सामान्यतः नई और चुनौतीपूर्ण होती हैं, जिनमें निर्णय लेने वाले के अंतर्ज्ञान और विवेक की आवश्यकता होती है। ये निर्णय अक्सर संगठन के शीर्ष नेतृत्व द्वारा लिए जाते हैं क्योंकि इनमें जोखिम की मात्रा अधिक होती है। ऐसे निर्णयों के सफल होने के लिए सृजनात्मकता और गहन विश्लेषण की अनिवार्य आवश्यकता होती है।

59. (A) जनरल से लेकर सिपाही तक एक सेना की कमान संरचना।
सेना की कमान संरचना पदसोपान के सिद्धांत का सबसे स्पष्ट उदाहरण है, जहाँ अधिकार और उत्तरदायित्व की एक स्पष्ट श्रृंखला होती है। इसमें प्रत्येक पद अपने ऊपर वाले पद के प्रति जवाबदेह होता है और नीचे वाले पद पर नियंत्रण रखता है। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि आदेशों का प्रवाह व्यवस्थित हो और संगठन में अनुशासन बना रहे। पदसोपान के कारण ही किसी भी बड़े संगठन में समन्वय स्थापित करना और कमान की अखंडता को बनाए रखना संभव हो पाता है।

60. (B) सामूहिक विचार-विमर्श और निर्णय लेना।
परिषद का मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत निरंकुशता को रोकना और विभिन्न हितों या विशेषज्ञों के ज्ञान को निर्णय प्रक्रिया में सम्मिलित करना है। इसमें सदस्य आपस में चर्चा करते हैं और सामूहिक रूप से नीतियाँ निर्धारित करते हैं। यह रूप लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देता है क्योंकि इसमें किसी एक व्यक्ति के बजाय बहुमत या सहमति के आधार पर कार्य किया जाता है। परिषदें विशेष रूप से नियामक कार्यों और उन क्षेत्रों में प्रभावी होती हैं जहाँ निष्पक्षता और व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है।

61. (C) स्टाफ एजेंसियों को प्रायः लगता है कि उनकी सलाह को लाइन एजेंसियों द्वारा उपेक्षित किया जाता है।
लाइन और स्टाफ के बीच संघर्ष का एक मुख्य कारण यह है कि स्टाफ विशेषज्ञ सलाह तो देते हैं, लेकिन उनके पास उसे लागू करने का कोई अधिकार नहीं होता। लाइन अधिकारी अक्सर इन सलाहों को अव्यावहारिक मानकर अनसुना कर देते हैं, जिससे स्टाफ में निराशा उत्पन्न होती है। दूसरी ओर, लाइन अधिकारियों को लगता है कि स्टाफ उनकी सत्ता में हस्तक्षेप कर रहे हैं। अधिकार और ज्ञान के बीच का यह असंतुलन संगठन में तनाव पैदा करता है, जो समन्वय को प्रभावित करता है।

62. (A) 2, 3, 1, 4
लोक प्रशासन के साहित्य का विकास अलग-अलग चरणों में हुआ। वुड्रो विल्सन का निबंध 1887 में आया, जिसने इस विषय की नींव रखी। इसके बाद 1930 के दशक में हाथोर्न प्रयोग हुए, जिन्होंने मानवीय व्यवहार पर प्रकाश डाला। हर्बर्ट साइमन की पुस्तक 1947 में प्रकाशित हुई। अंततः फ्रेड रिग्स ने 1961 में अपनी प्रसिद्ध रचना के माध्यम से प्रशासनिक अध्ययन में पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण को लोकप्रिय बनाया, जो विकासशील समाजों के लिए महत्वपूर्ण था। यह क्रम इस विषय के बौद्धिक विकास को दर्शाता है।

63. (C) विधि-व्यवस्था के कार्यों से सामाजिक-आर्थिक विकास कार्यों की ओर।
पारंपरिक प्रशासन का मुख्य कार्य राज्य में शांति और व्यवस्था बनाए रखना तथा कर वसूलना था। इसके विपरीत, विकास प्रशासन का लक्ष्य समाज का सर्वांगीण कल्याण और प्रगति है। इसमें सरकार की भूमिका केवल एक नियामक की नहीं, बल्कि एक उत्प्रेरक और समाज निर्माता की होती है। यह दृष्टिकोण राष्ट्रों को गरीबी से निकालकर आधुनिकता की ओर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। अतः यह विधिक सीमाओं से आगे बढ़कर वास्तविक मानवीय विकास की दिशा में एक बड़ा संरचनात्मक बदलाव है।

NODIA

64. (D) न्यायिक
मुख्य कार्यपालिका के विभिन्न प्रकारों में एकल, बहुल और अध्यक्षीय या संसदीय प्रणालियाँ सम्मिलित हैं। न्यायिक कार्यपालिका का कोई स्वतंत्र प्रकार नहीं होता, क्योंकि न्यायपालिका शासन का एक अलग और स्वतंत्र अंग है। मुख्य कार्यपालिका मुख्य रूप से नीतियों को लागू करने और प्रशासन का नेतृत्व करने के लिए उत्तरदायी होती है। एकल कार्यपालिका में शक्ति एक व्यक्ति में होती है, जबकि बहुल कार्यपालिका में यह समूह में विभाजित होती है। न्यायिक कार्य केवल कानून की व्याख्या से संबंधित होते हैं।

65. (B) विभाग
सरकारी गतिविधियों को संगठित करने का सबसे पारंपरिक और व्यापक रूप विभाग है। प्रत्येक विभाग किसी विशिष्ट कार्य, जैसे रक्षा या शिक्षा, के लिए उत्तरदायी होता है और इसका नेतृत्व एक मंत्री करता है। विभाग सीधे सरकार के प्रशासनिक ढांचे का हिस्सा होते हैं और उनके पास उत्तरदायित्व की एक स्पष्ट पदसोपानिक श्रृंखला होती है। यह ढाँचा सरकारी नीतियों पर प्रभावी नियंत्रण और निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है और वर्तमान में दुनिया भर के देशों में प्रचलित है।

66. (A) वुड्रो विल्सन
वुड्रो विल्सन ने ही पहली बार लोक प्रशासन को राजनीति विज्ञान के एक स्वतंत्र अंग के रूप में देखने पर बल दिया था। उन्होंने तर्क दिया कि प्रशासन का अध्ययन राजनीति की जटिलताओं से अलग होना चाहिए ताकि इसे एक वैज्ञानिक आधार दिया जा सके। उनके अनुसार, प्रशासन को चलाने के लिए विशिष्ट सिद्धांतों और तकनीकों की आवश्यकता होती है। उनके इस दृष्टिकोण ने लोक प्रशासन को एक नई शैक्षणिक पहचान प्रदान की और इसके स्वतंत्र अकादमिक विकास का मार्ग प्रशस्त किया।

उत्पादकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसने संगठनों को केवल एक यांत्रिक संरचना के रूप में देखने के बजाय एक सामाजिक प्रणाली के रूप में देखने पर बल दिया, जहाँ मानवीय भावनाओं का सम्मान अनिवार्य है।

49. (C) संगठनात्मक पदसोपान के भीतर निचले स्तरों को।
विकेंद्रीकरण एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था है जिसमें निर्णय लेने की शक्ति और अधिकार केवल शीर्ष प्रबंधन तक सीमित नहीं रहते, बल्कि उन्हें संगठन के विभिन्न निचले स्तरों में वितरित कर दिया जाता है। इसका उद्देश्य निर्णय लेने की प्रक्रिया को त्वरित बनाना और स्थानीय समस्याओं के प्रति अधिक संवेदनशील होना है। यह कनिष्ठ अधिकारियों को सशक्त बनाता है और उन्हें भविष्य के नेतृत्व के लिए तैयार करता है। विकेंद्रीकरण से प्रशासनिक कार्यभार का वितरण होता है और जनता की सहभागिता में वृद्धि होती है।

50. (B) विधि की अनुशंसा करना, अध्यादेश जारी करना और वीटो शक्ति का उपयोग करना।
मुख्य कार्यपालिका का विधायी कार्य नीति निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप को दर्शाता है। वह विधायिका को नए कानूनों के लिए सुझाव भेजती है और संसद का सत्र न होने पर अध्यादेश जारी कर सकती है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रपति के पास विधेयकों पर वीटो करने की शक्ति होती है, जिससे वे किसी कानून को बनने से रोक सकते हैं। ये शक्तियाँ कार्यपालिका को विधायी प्रक्रिया का एक अभिन्न और प्रभावशाली हिस्सा बनाती हैं, जो शक्ति संतुलन सुनिश्चित करती हैं।

51. (D) औपचारिक कानूनी निर्देशों और वास्तविक प्रशासनिक अभ्यास के बीच एक बड़ा अंतर।
रिग्स के प्रिज्मीय मॉडल में औपचारिकतावाद उस स्थिति को दर्शाता है जहाँ कागज पर लिखे नियम और वास्तविकता में किए जाने वाले कार्यों के बीच कोई तालमेल नहीं होता। उदाहरण के लिए, भ्रष्टाचार विरोधी कानून मौजूद हो सकते हैं, लेकिन व्यवहार में अनियमितताएं व्यापक हो सकती हैं। यह लक्षण संक्रमणकालीन समाजों की प्रशासनिक विफलता का एक प्रमुख कारण है। यहाँ नियमों का पालन करने का केवल दिखावा किया जाता है, जबकि निर्णय व्यक्तिगत संबंधों या पुरानी परंपराओं के आधार पर लिए जाते हैं।

52. (A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
नियंत्रण का क्षेत्र सीधे तौर पर संगठन की संरचना को प्रभावित करता है। जब एक प्रबंधक के अधीन अधीनस्थों की संख्या अधिक होती है, तो उसे विस्तृत क्षेत्र कहा जाता है, जिससे प्रबंधन के स्तर कम हो जाते हैं और संगठन सपाट दिखता है। इसके विपरीत, संकीर्ण क्षेत्र में अधीनस्थों की संख्या कम होने से प्रबंधन के कई स्तर बन जाते हैं, जिससे संगठन लंबवत हो जाता है। ये दोनों स्थितियाँ संगठन में संचार और पर्यवेक्षण की गति को अलग-अलग प्रकार से प्रभावित करती हैं।

53. (C) संगठन को एक बंद व्यवस्था के रूप में मानना और मानवीय तत्व की उपेक्षा करना।
शास्त्रीय संगठन सिद्धांत की मुख्य आलोचना यह है कि यह संगठनों को एक बंद मशीन की तरह देखता है जो अपने बाहरी वातावरण से अप्रभावित रहती है। यह सिद्धांत केवल संरचना, नियमों और आर्थिक दक्षता पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि श्रमिकों की भावनाओं और मनोवैज्ञानिक पहलुओं को पूरी तरह नकार देता है। इसे बिना मनुष्य का संगठन भी कहा जाता है। आधुनिक विचारक मानते हैं कि मानवीय आवश्यकताओं और बाहरी कारकों की उपेक्षा करने वाला संगठन लंबे समय तक सफल नहीं हो सकता।

54. (A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
लोक निगमों का गठन विशेष रूप से उन सरकारी व्यवसायों के लिए किया जाता है जिन्हें गति और लचीलेपन की आवश्यकता होती है। सरकारी विभाग प्रायः लालफीताशाही और बजटीय सीमाओं से बंधे होते हैं, जो औद्योगिक संचालन के लिए उपयुक्त नहीं हैं। लोक निगमों को अपनी वित्तीय नीतियाँ बनाने और व्यावसायिक निर्णय लेने की स्वायत्तता प्राप्त होती है। यह स्वायत्तता उन्हें निजी क्षेत्र की तरह प्रतिस्पर्धी और कुशल बनाने के उद्देश्य से प्रदान की जाती है ताकि वे उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें।

55. (D) विभागों के प्रमुखों की नियुक्ति करना, उन्हें निर्देशित करना और पदमुक्त करना।
मुख्य कार्यपालिका की प्रशासनिक भूमिका शासन के सुचारु संचालन को सुनिश्चित करने से जुड़ी है। इसमें वह अपने अधीनस्थ विभागों के लिए कुशल नेतृत्व का चयन करती है और उनके कार्यों की नियमित देखरेख करती है। अधिकारियों को दिशा-निर्देश देना और आवश्यकतानुसार उन्हें पद से हटाना प्रशासनिक नियंत्रण बनाए रखने का एक सशक्त माध्यम है। इस प्रक्रिया के माध्यम से मुख्य कार्यपालिका पूरे सरकारी तंत्र पर अपना प्रभावी प्रभुत्व स्थापित करती है और नीतियों के सफल क्रियान्वयन के लिए जवाबदेही तय करती है।

56. (B) अपने परिवर्तनशील बाहरी वातावरण के अनुकूल होना।
व्यवस्था दृष्टिकोण के अनुसार, एक संगठन एक खुली व्यवस्था है जो लगातार अपने बाहरी परिवेश से प्रभावित होती है। इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तनों के अनुसार खुद को कितनी तेजी से ढाल सकता है। जो संगठन अपने वातावरण से प्राप्त प्रतिपुष्टि की उपेक्षा करते हैं और लचीले नहीं होते, वे धीरे-धीरे अप्रचलित हो जाते हैं। अनुकूलनशीलता और बाहरी जगत के साथ संतुलन बनाए रखना ही दीर्घकालिक प्रभावशीलता की कुंजी मानी जाती है।

57. (A) केवल 1 और 2
शास्त्रीय विचारधारा के अंतर्गत श्रम विभाजन और आदेश की एकता जैसे सिद्धांतों को संगठन की दक्षता बढ़ाने के लिए अनिवार्य माना गया है। श्रम विभाजन से विशेषज्ञता बढ़ती है, जबकि आदेश की एकता अनुशासन सुनिश्चित करती है। सीमित तर्कसंगतता इस विचारधारा का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह

Click Here to Buy book on Amazon

95. (B) अर्ध-विधायी शक्ति
जब मुख्य कार्यपालिका कार्यकारी आदेश जारी करती है, तो वह वास्तव में कानून बनाने जैसी भूमिका निभा रही होती है, जिसे अर्ध-विधायी शक्ति कहा जाता है। ये आदेश कानून के समान ही बाध्यकारी होते हैं और प्रशासनिक स्पष्टता लाने के लिए जारी किए जाते हैं। विधायिका हर विस्तार पर कानून नहीं बना सकती, इसलिए वह कार्यपालिका को नियमों को परिभाषित करने की शक्ति प्रदान करती है। यह शक्ति कार्यपालिका को नीतियों के त्वरित कार्यान्वयन में सक्षम बनाती है, जिससे शासन व्यवस्था में लचीलापन और कार्यक्षमता बढ़ती है।

96. (B) संगठन के निचले स्तरों पर अधिकार का प्रसार।
विकेंद्रीकरण का अर्थ है अधिकार और उत्तरदायित्व को पदसोपान के विभिन्न स्तरों पर बाँटना। इसमें शीर्ष प्रबंधन केवल नीतिगत विषयों पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि परिचालन संबंधी निर्णय लेने की शक्ति क्षेत्रीय या स्थानीय अधिकारियों को दी जाती है। इससे निर्णय लेने में लगने वाला समय कम होता है और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार नीतियाँ बनाई जा सकती हैं। विकेंद्रीकरण न केवल प्रशासन को अधिक लोकतांत्रिक बनाता है, बल्कि यह कनिष्ठ कर्मचारियों के कौशल और आत्मविश्वास को विकसित करने में सहायक होता है।

97. (B) एल्टन मेयो
एल्टन मेयो ने 1920 और 1930 के दशकों में शिकागो की एक कंपनी में प्रसिद्ध हाथोर्न प्रयोगों का नेतृत्व किया था। इन प्रयोगों ने संगठनात्मक व्यवहार की हमारी समझ को पूरी तरह बदल दिया। मेयो ने यह निष्कर्ष निकाला कि कार्यस्थल की भौतिक स्थितियाँ उतनी महत्वपूर्ण नहीं हैं जितनी कि कर्मचारियों की सामाजिक मान्यता और समूह में उनकी स्थिति। उनके इन निष्कर्षों ने ही मानव संबंध आंदोलन को जन्म दिया, जिसने प्रबंधन में मानवीय संवेदनाओं और अनौपचारिक संबंधों को केंद्रीय स्थान प्रदान किया।

98. (A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
औपचारिक और अनौपचारिक संगठन किसी भी संस्था के दो अभिन्न अंग हैं। औपचारिक संगठन सचेत रूप से बनाया जाता है और इसके नियम व संरचनाएँ लिखित एवं स्पष्ट होती हैं। इसके विपरीत, अनौपचारिक संगठन कर्मचारियों के बीच स्वाभाविक रूप से पनपने वाले सामाजिक संबंधों का परिणाम होता है। जहाँ औपचारिक संगठन स्थिरता और व्यवस्था प्रदान करता है, वहीं अनौपचारिक संगठन मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करता है। ये दोनों मिलकर संगठन की समग्र कार्य संस्कृति और दक्षता को गहराई से प्रभावित करते हैं।

99. (C) वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई व्यवस्था अपनी संरचना बनाए रखने के लिए व्यय की गई ऊर्जा से अधिक ऊर्जा आयात करती है।
व्यवस्था दृष्टिकोण में एन्ट्रॉपी किसी व्यवस्था के क्षय होने की प्राकृतिक प्रवृत्ति को दर्शाती है। इससे बचने के लिए, एक खुली व्यवस्था बाहरी वातावरण से निरंतर ऊर्जा और सूचना प्राप्त करती है, जिसे नकारात्मक एन्ट्रॉपी कहा जाता है। यह अतिरिक्त ऊर्जा व्यवस्था को न केवल जीवित रखती है बल्कि उसे विकसित और सुदृढ़ भी बनाती है। इस प्रक्रिया के माध्यम से संगठन अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करता है और बाहरी चुनौतियों का सामना करने के लिए आवश्यक संसाधन जुटाता है, जिससे निरंतरता बनी रहती है।

100. (A) 3, 2, 1, 4
संगठन के सिद्धांतों का क्रमिक विकास प्रशासनिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। 20वीं सदी के प्रारंभ में फ्रेडरिक टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंधन के माध्यम से कार्य कुशलता पर ध्यान दिया। 1930 के दशक में एल्टन मेयो ने मानव संबंध के सामाजिक पक्ष को उजागर किया। इसके बाद हर्बर्ट साइमन ने व्यवहारवाद के माध्यम से निर्णय लेने की प्रक्रिया का विश्लेषण किया। अंत में, आकस्मिकता सिद्धांत ने यह प्रतिपादित किया कि प्रबंधन की शैलियाँ परिस्थितियों के अनुसार बदलनी चाहिए, जो एक आधुनिक विचारधारा है।

101. (C) तर्कसंगत-व्यापक मॉडल
तर्कसंगत-व्यापक मॉडल इस आदर्श स्थिति की कल्पना करता है जहाँ निर्णय लेने वाले के पास समस्या से संबंधित सभी सूचनाएँ उपलब्ध होती हैं। वह सभी संभावित विकल्पों का विश्लेषण करता है और उनके परिणामों की तुलना करके सर्वोत्तम विकल्प का चयन करता है। इस मॉडल को आर्थिक मानव के विचार के साथ जोड़ा जाता है। हालाँकि, वास्तविक प्रशासनिक परिस्थितियों में पूर्ण सूचना और असीमित समय का अभाव होता है, जिससे इस मॉडल की व्यवहार्यता सीमित हो जाती है। फिर भी, यह तार्किक निर्णय प्रक्रिया का मानक है।

102. (C) एक लोक निगम
लोक निगम संगठन का एक अनूठा रूप है जो सरकारी स्वामित्व और व्यावसायिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन स्थापित करता है। यह सार्वजनिक हितों की रक्षा करने के साथ-साथ निजी क्षेत्र की तरह लचीलेपन के साथ कार्य करता है। इसे संसद के अधिनियम द्वारा बनाया जाता है, जिससे इसे वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त होती है। यह उन सार्वजनिक सेवाओं के लिए आदर्श है जिन्हें सरकारी नियमों की कठोरता से बचाकर व्यावसायिक आधार पर कुशलतापूर्वक संचालित करने की आवश्यकता होती है, जैसे परिवहन या बैंकिंग सेवाएँ।

103. (A) पारंपरिक और अविभेदित है, जहाँ एक ही संरचना कई कार्य करती है।
फ्रेड रिग्स के अनुसार, संग्लन समाज वह होता है जहाँ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य एक ही संस्था द्वारा किए जाते हैं। यहाँ कार्यों का कोई विशेषीकरण नहीं होता। उदाहरण के लिए, एक मुखिया ही न्याय भी करता है, कर भी वसूलता है और सेना का नेतृत्व भी करता है। यह समाज आधुनिकता से दूर और पूरी तरह से पारंपरिक होता है। रिग्स ने इस मॉडल का उपयोग प्राचीन और अपेक्षाकृत पिछड़े समाजों की प्रशासनिक व्यवस्था को स्पष्ट करने के लिए किया था।

NODIA

67. (C) मानव संबंध सिद्धांत
मानव संबंध सिद्धांत ने शास्त्रीय सिद्धांतों की यांत्रिक धारणा को बदलते हुए यह सिद्ध किया कि कर्मचारी केवल धन के लिए काम नहीं करते। एल्टन मेयो और उनके साथियों ने हाथोर्न प्रयोगों के माध्यम से दिखाया कि कार्यस्थल पर अनौपचारिक समूहों का अस्तित्व और बेहतर संचार उत्पादकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस सिद्धांत ने यह स्पष्ट किया कि जब श्रमिकों को सम्मान और पहचान मिलती है, तो वे अधिक कुशलता के साथ अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं और संतुष्ट रहते हैं।

68. (A) आकस्मिकता सिद्धांत
आकस्मिकता सिद्धांत का मूल मंत्र यह है कि प्रबंधन का कोई भी नियम सार्वभौमिक रूप से हर स्थिति में सही नहीं हो सकता। संगठन की संरचना और कार्यप्रणाली उस समय की परिस्थितियों, जैसे कि तकनीक और वातावरण की अनिश्चितता, पर निर्भर करनी चाहिए। यह सिद्धांत प्रबंधकों को लचीला होने की सलाह देता है और यह मानता है कि विभिन्न चुनौतियों के लिए अलग-अलग समाधानों की आवश्यकता होती है। यह शास्त्रीय सिद्धांतों के एक सर्वोत्तम विधि के दावे को पूरी तरह नकारता है।

69. (C) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
केंद्रीकरण नीतियों में एकरूपता और कड़ा अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी होता है। हालाँकि, विकेंद्रीकरण के बारे में कथन II गलत है क्योंकि वास्तव में विकेंद्रीकरण से कर्मचारी मनोबल में वृद्धि होती है। जब कर्मचारियों को निर्णय लेने की स्वतंत्रता और जिम्मेदारी दी जाती है, तो वे अधिक प्रेरित महसूस करते हैं। विकेंद्रीकरण स्थानीय स्तर पर निर्णयों में तेजी लाता है क्योंकि फाइलें ऊपर भेजने की आवश्यकता नहीं होती। अतः विकेंद्रीकरण संगठन को अधिक गतिशील और कुशल बनाता है।

70. (A) P-4, Q-3, R-2, S-1
लोक प्रशासन के विभिन्न विचारकों ने विशिष्ट क्षेत्रों में योगदान दिया है। हेनरी फेयोल ने प्रबंधन के 14 सामान्य सिद्धांतों को प्रतिपादित किया, जबकि टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंधन का मार्ग दिखाया। एल्टन मेयो को उनके हाथोर्न प्रयोगों के लिए जाना जाता है जिन्होंने मानवीय संबंधों के महत्व को उजागर किया। मैक्स वेबर ने नौकरशाही का एक आदर्श मॉडल प्रस्तुत किया जो तर्कसंगतता और नियमों पर आधारित था। ये सभी सिद्धांत मिलकर आधुनिक संगठनात्मक समझ और प्रशासनिक कौशल का आधार निर्मित करते हैं।

71. (B) आकस्मिकता दृष्टिकोण
आकस्मिकता दृष्टिकोण यह मानता है कि एक संगठन की प्रभावशीलता उसकी संरचना और बाहरी वातावरण के बीच के तालमेल पर निर्भर करती है। इसके अनुसार, बड़े आकार के संगठनों को अधिक औपचारिकता की आवश्यकता हो सकती है, जबकि जटिल तकनीक वाले संगठनों को अधिक लचीलेपन की। कोई भी एक संगठनात्मक मॉडल हर स्थिति में सफल नहीं हो सकता। अतः, प्रबंधकों को अपनी रणनीतियाँ उस विशिष्ट परिस्थिति के अनुसार बदलनी चाहिए जिसमें उनका संगठन कार्य कर रहा है, ताकि सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त हो सकें।

72. (B) जटिलता और विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता को संभालना।
जैसे-जैसे संगठन बढ़ते हैं, उनके कार्यों में जटिलता और तकनीकी बारीकियां भी बढ़ जाती हैं। लाइन प्रबंधकों के पास हर क्षेत्र का गहन ज्ञान होना संभव नहीं होता। इसलिए, स्टाफ पदों का सृजन किया जाता है ताकि वे वित्त या तकनीकी विषयों पर विशेषज्ञ परामर्श प्रदान कर सकें। ये पद लाइन अधिकारियों को भारी कार्यभार से मुक्त करते हैं और उन्हें बेहतर निर्णय लेने में सहायता करते हैं। स्टाफ का मुख्य उद्देश्य संगठन की बौद्धिक क्षमता और योजना शक्ति को सुदृढ़ करना होता है।

73. (B) पर्यवेक्षण और समन्वय
नियंत्रण के क्षेत्र का सीधा संबंध इस बात से है कि एक प्रबंधक अपने अधीनस्थों के कार्यों का कितनी सटीकता से पर्यवेक्षण कर सकता है। यदि यह क्षेत्र बहुत बड़ा है, तो प्रबंधक प्रत्येक व्यक्ति पर ध्यान नहीं दे पाएगा, जिससे समन्वय बिगड़ सकता है और कार्य की गुणवत्ता गिर सकती है। इसके विपरीत, बहुत छोटा क्षेत्र होने पर अनावश्यक हस्तक्षेप की समस्या उत्पन्न हो सकती है। अतः, एक प्रभावी संगठन में पर्यवेक्षण की सीमा ऐसी होनी चाहिए जो अनुशासन और कार्यकुशलता के बीच सही संतुलन बनाए रखे।

74. (A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
व्यवस्था दृष्टिकोण संगठन को एक सजीव और गतिशील प्रणाली के रूप में देखता है जो अपने बाहरी वातावरण के साथ निरंतर विनिमय करती है। यह खुली व्यवस्था का विचार इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कोई भी संगठन निर्वात में कार्य नहीं कर सकता। वह समाज से संसाधन प्राप्त करता है और उन्हें सेवाओं के रूप में समाज को लौटाता है। वातावरण के साथ यह निरंतर अंतःक्रिया संगठन को बदलने और बाहरी चुनौतियों का सामना करने की क्षमता प्रदान करती है। यह निरंतरता के लिए अनिवार्य है।

75. (C) संदेशों, वीटो और नीति प्रस्तावों के माध्यम से विधि निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करना।
यद्यपि कानून बनाना मुख्य रूप से विधायिका का कार्य है, लेकिन मुख्य कार्यपालिका इस प्रक्रिया को गहराई से प्रभावित करती है। वह नए विधेयकों की अनुशंसा करती है और बजट के माध्यम से अपनी प्राथमिकताओं को कानून का रूप दिलाती है। वीटो शक्ति उसे अनुचित कानूनों को रोकने का अधिकार देती है। इसके अलावा, वह अपने सार्वजनिक संदेशों के माध्यम से जनमत तैयार करती है, जिससे विधायी एजेंडा निर्धारित होता है। इस प्रकार, कार्यपालिका विधायी प्रक्रिया की एक मार्गदर्शक शक्ति के रूप में कार्य करती है।

76. (B) आधुनिक विशिष्ट संरचनाएं उपस्थित हैं, लेकिन पुरानी अविभेदित संरचनाएं उन कार्यों को करना जारी रखती हैं।
रिग्स के प्रिज्मीय समाज में अतिव्यापन वह स्थिति है जहाँ आधुनिक प्रशासन के ढांचे और वास्तविक पारंपरिक प्रथाओं के बीच टकराव होता है। यहाँ एक तरफ तो विशेष सरकारी

Downloaded from www.pdf.tube

एजेंसियाँ होती हैं, लेकिन दूसरी तरफ धर्म या जाति जैसे पारंपरिक कारक अभी भी प्रशासनिक निर्णयों को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, योग्यता के आधार पर भर्ती का नियम तो होता है, लेकिन व्यवहार में व्यक्तिगत वफादारी का बोलबाला रहता है। यह प्रशासनिक प्रणाली में अस्पष्टता और अकुशलता उत्पन्न करता है।

77. (B) यह व्यक्तिगत संबंधों और सामाजिक नेटवर्क पर आधारित होता है।
अनौपचारिक संगठन का उदय औपचारिक ढांचे के भीतर काम करने वाले लोगों की सामाजिक आवश्यकताओं के कारण होता है। यह लिखित नियमों के बजाय व्यक्तिगत पसंद और मित्रता के माध्यम से संचालित होता है। ऐसे संगठनों में अधिकार पद के बजाय व्यक्तिगत प्रभाव पर आधारित होता है। ये संगठन औपचारिक संचार की कमियों को दूर कर सकते हैं और कर्मचारियों के बीच एकता की भावना पैदा करते हैं। हालाँकि, कभी-कभी ये आधिकारिक लक्ष्यों में बाधा भी उत्पन्न कर सकते हैं यदि इनके हित विपरीत हों।

78. (A) अनियोजित निर्णय
जब कोई संगठन पूरी तरह से नई और अनिश्चित स्थिति का सामना करता है, जैसे कि किसी नए बाजार में प्रवेश करना, तो इसके लिए लिए जाने वाले निर्णय अनियोजित कहलाते हैं। इन निर्णयों के लिए कोई पिछला उदाहरण या निर्धारित नियम मौजूद नहीं होता। इनमें बहुत अधिक जोखिम और अनिश्चितता होती है, इसलिए इन्हें लेने के लिए उच्च स्तरीय रचनात्मकता और रणनीतिक सोच की आवश्यकता होती है। ये निर्णय संगठन के भविष्य की दिशा तय करते हैं और प्रायः शीर्ष प्रबंधकों द्वारा लिए जाते हैं।

79. (D) लाइन एजेंसी
विदेश मंत्रालय एक लाइन एजेंसी का उत्कृष्ट उदाहरण है क्योंकि यह भारत सरकार के विदेशी संबंधों और कूटनीति के प्राथमिक उद्देश्यों को सीधे तौर पर पूरा करता है। लाइन एजेंसियाँ वे होती हैं जो संगठन के मुख्य लक्ष्यों के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार होती हैं और सीधे बाहरी दुनिया के साथ अंतःक्रिया करती हैं। इस मंत्रालय के पास अपने कार्यक्षेत्र में निर्णय लेने और उन्हें लागू करने का पूर्ण अधिकार होता है। यह सरकार की नीतियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्रियान्वित करने वाली अग्रिम इकाई है।

80. (B) राष्ट्रीय विकास के लिए योजनाओं और कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना।
विकास प्रशासन का मुख्य सरोकार केवल नियम बनाए रखना नहीं है, बल्कि राष्ट्र की प्रगति के लिए सक्रिय रूप से कार्य करना है। इसका उद्देश्य प्रशासनिक तंत्र को इतना सक्षम बनाना है कि वह आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन की बड़ी परियोजनाओं को कुशलतापूर्वक पूरा कर सके। यह प्रशासन नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने और राष्ट्र निर्माण के व्यापक लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहता है। यह लोक प्रशासन के पारंपरिक ढांचे में कार्यक्षमता और सकारात्मक उद्देश्यपरकता का संचार करने में सहायक होता है।

81. (A) नियंत्रण का एक संकीर्ण क्षेत्र और कई पदसोपानिक स्तर।
एक लंबवत संगठनात्मक संरचना में प्रत्येक प्रबंधक के पास केवल कुछ ही अधीनस्थ होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप संगठन में ऊपर से नीचे तक कई पदसोपानिक स्तर बन जाते हैं। इस संरचना में वरिष्ठ अधिकारी अपने अधीनस्थों के कार्य पर बहुत सूक्ष्मता से नजर रख सकते हैं। हालाँकि, इसकी एक बड़ी कमी यह है कि सूचनाओं को ऊपर से नीचे पहुँचने में बहुत समय लगता है, जिससे संचार धीमा हो जाता है। यह संरचना कठोर अनुशासन और कड़े नियंत्रण वाले संगठनों में अधिक प्रचलित है।

82. (B) आदेशों की वह सीमा जिसे एक कर्मचारी सचेत रूप से प्राधिकार पर प्रश्न उठाए बिना स्वीकार करने को तत्पर है।
चेस्टर बर्नार्ड के अनुसार, प्रत्येक कर्मचारी के मन में एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ वह अपने वरिष्ठ के आदेशों को बिना किसी हिचकिचाहट के स्वीकार कर लेता है। इसे उदासीनता का क्षेत्र कहा जाता है। यदि कोई आदेश इस क्षेत्र से बाहर होता है, तो कर्मचारी उसे स्वीकार करने में संकोच कर सकता है या विरोध कर सकता है। एक सफल प्रबंधक वही है जो इस क्षेत्र का विस्तार कर सके और अपने अधीनस्थों में ऐसा विश्वास पैदा करे कि वे उसके निर्देशों का सहज पालन करें।

83. (A) केवल 1 और 2
पदसोपान का सिद्धांत संगठन में वरिष्ठ और अधीनस्थ के बीच एक स्पष्ट अधिकार श्रृंखला स्थापित करता है। यह सुनिश्चित करता है कि आदेश ऊपर से नीचे व्यवस्थित रूप से प्रवाहित हों और जवाबदेही बनी रहे। कथन 3 गलत है क्योंकि पदसोपान वास्तव में सीधा संचार को हतोत्साहित करता है और एक निश्चित क्रम में संचार पर बल देता है। यह सिद्धांत संगठन में अनुशासन बनाए रखने और कार्यों के दोहराव को रोकने के लिए अत्यंत आवश्यक माना जाता है, जिससे स्पष्टता बनी रहती है।

84. (B) एक वास्तविक कार्यपालिका जो राज्य का प्रमुख नहीं है।
संसदीय प्रणाली में, प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका होता है क्योंकि वह सरकार की शक्तियों का वास्तविक प्रयोग करता है और मंत्रिमंडल का नेतृत्व करता है। हालाँकि, वह राज्य का प्रमुख नहीं होता; यह पद राष्ट्रपति के पास होता है जो केवल नाममात्र की शक्तियों का प्रयोग करते हैं। प्रधानमंत्री अपनी शक्तियों के लिए सीधे संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह बनी रहे, जो आधुनिक लोकतंत्र की एक आधारभूत और अनिवार्य विशेषता है।

85. (C) विधायिका का एक विशिष्ट अधिनियम।
लोक निगमों का निर्माण किसी कार्यकारी आदेश के बजाय विधायिका द्वारा पारित एक विशेष कानून के माध्यम से किया जाता है। यह अधिनियम निगम के उद्देश्यों, शक्तियों, वित्तीय स्वायत्तता और उत्तरदायित्व के दायरे को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। कानून द्वारा निर्मित होने के कारण, लोक निगमों को एक स्वतंत्र कानूनी व्यक्तित्व प्राप्त होता है, जो उन्हें सरकारी विभागों की तुलना में अधिक स्थिरता प्रदान करता है।

NODIA

यह सुनिश्चित करता है कि निगम जनहित और व्यावसायिक दक्षता के बीच सही संतुलन बनाए रखें।

86. (A) मानव संबंध सिद्धांत
मानव संबंध सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि कार्यस्थल पर उत्पादकता केवल भौतिक सुख-सुविधाओं से नहीं बढ़ती, बल्कि कर्मचारियों की सामाजिक और मनोवैज्ञानिक संतुष्टि से बढ़ती है। मनुष्य अपनी पहचान और समूह में स्वीकार्यता की आवश्यकता से प्रेरित होते हैं। एल्टन मेयो ने सिद्ध किया कि जब कर्मचारी खुद को एक महत्वपूर्ण समूह का हिस्सा महसूस करते हैं, तो वे अधिक स्वेच्छा से कार्य करते हैं। इसने संगठनों को केवल एक यांत्रिक संरचना के बजाय एक सामाजिक प्रणाली के रूप में देखा।

87. (B) सीमित तर्कसंगतता
हेनरी फेयोल ने प्रबंधन के 14 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था, जिनमें कार्य का विभाजन और सोपानिक श्रृंखला सम्मिलित हैं। सीमित तर्कसंगतता फेयोल का सिद्धांत नहीं है, बल्कि इसे हर्बर्ट साइमन ने अपने निर्णय-निर्माण सिद्धांत में प्रस्तुत किया था। फेयोल के सिद्धांत संगठन की औपचारिक संरचना और प्रबंधन प्रक्रियाओं को व्यवस्थित करने पर केंद्रित थे। उनके विचारों ने आधुनिक प्रशासनिक प्रबंधन की नींव रखी और यह समझाया कि किस प्रकार एक प्रभावी नेतृत्व संगठन के लक्ष्यों को कुशलतापूर्वक प्राप्त कर सकता है।

88. (C) कार्य और अधिकार
लाइन और स्टाफ इकाइयों के बीच प्राथमिक अंतर उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों और उनके पास उपलब्ध अधिकार में निहित है। लाइन इकाइयों के पास आदेश देने और नीतियों को सीधे लागू करने का अधिकार होता है, क्योंकि वे संगठन के मुख्य लक्ष्यों के लिए जिम्मेदार होती हैं। इसके विपरीत, स्टाफ इकाइयों का कार्य केवल परामर्श प्रदान करना और लाइन अधिकारियों की सहायता करना है। उनके पास किसी को आदेश देने की शक्ति नहीं होती। यह विभाजन संगठन में विशेषज्ञता और कार्यकारी नियंत्रण के बीच संतुलन बनाता है।

89. (C) अधिक कर्मचारी स्वायत्तता और तीव्र संचार।
नियंत्रण के विस्तृत क्षेत्र वाली सपाट संरचना में प्रबंधन के स्तर कम होते हैं, जिससे सूचनाएं ऊपर से नीचे बहुत तेजी से पहुँचती हैं। चूँकि एक प्रबंधक के पास कई अधीनस्थ होते हैं, वह प्रत्येक के कार्य में अधिक हस्तक्षेप नहीं कर पाता, जिससे कर्मचारियों को अपने निर्णय स्वयं लेने की अधिक स्वायत्तता मिलती है। यह वातावरण कर्मचारियों में जिम्मेदारी की भावना और सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है। यह उन संगठनों के लिए बहुत प्रभावी है जहाँ कर्मचारी अनुभवी और कार्य में पूरी तरह कुशल होते हैं।

90. (C) विशिष्ट ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक वातावरण के संबंध में।
पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण इस बात पर जोर देता है कि लोक प्रशासन निर्वात में कार्य नहीं करता। किसी देश का प्रशासन वहाँ की संस्कृति, अर्थव्यवस्था और राजनीति की उपज होता है। उदाहरण के लिए, एक विकसित देश का प्रशासनिक मॉडल किसी विकासशील देश में तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक उसे स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल न ढाला जाए। यह दृष्टिकोण प्रशासन के तुलनात्मक अध्ययन को अधिक वैज्ञानिक बनाता है और बताता है कि वातावरण प्रशासनिक प्रणालियों को कैसे निरंतर प्रभावित और परिवर्तित करता है।

91. (A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
आदेश की एकता का सिद्धांत प्रशासनिक दक्षता का एक स्तंभ है। यदि एक अधीनस्थ को दो या दो से अधिक वरिष्ठों से अलग-अलग निर्देश मिलते हैं, तो वह असमंजस में पड़ सकता है और कार्य में विलंब हो सकता है। यह स्थिति अनुशासनहीनता और जवाबदेही की कमी का कारण बनती है। एक ही अधिकारी होने से कर्मचारी को अपनी प्राथमिकताओं का स्पष्ट पता होता है और वह अपनी पूरी ऊर्जा कार्य को निष्पादित करने में लगा सकता है। इससे संगठन में सामंजस्य बना रहता है।

92. (C) साक्षरता, सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक विकास जैसे क्षेत्रों में मूर्त उपलब्धियां।
विकास प्रशासन की सफलता का असली पैमाना केवल कागजी कार्रवाई नहीं है, बल्कि समाज में आने वाला वास्तविक बदलाव है। इसकी प्रभावशीलता इस बात से मापी जाती है कि सरकार अपनी विकास योजनाओं के माध्यम से लोगों के जीवन स्तर को कितना सुधार पाई है। गरीबी में कमी और बुनियादी ढाँचे का निर्माण ही इसके वास्तविक परिणाम हैं। यह प्रशासन परिणाम-उन्मुख होता है और इसका अंतिम लक्ष्य राष्ट्र का समग्र और समावेशी सामाजिक-आर्थिक उत्थान करना है, जो इसकी सार्थकता सिद्ध करता है।

93. (C) चेस्टर आई. बर्नार्ड
चेस्टर बर्नार्ड ने संगठन को एक सहकारी प्रणाली के रूप में परिभाषित किया, जहाँ सफलता व्यक्तियों के बीच सहयोग प्राप्त करने की क्षमता पर निर्भर करती है। उनके अनुसार, एक कार्यपालिका का सबसे महत्वपूर्ण कार्य संचार की व्यवस्था बनाए रखना और कर्मचारियों को संगठन के प्रति समर्पित होने के लिए प्रेरित करना है। बर्नार्ड ने तर्क दिया कि संगठन तभी जीवित रह सकते हैं जब वे सदस्यों की व्यक्तिगत जरूरतों और संगठनात्मक उद्देश्यों के बीच संतुलन बनाए रखें। उनका यह विचार प्रबंधन के सामाजिक पक्ष को उजागर करता है।

94. (C) राजनीतिक हस्तक्षेप और कठोर वित्तीय प्रक्रियाएं।
जब किसी व्यावसायिक कार्य को सरकारी विभाग के माध्यम से चलाया जाता है, तो वह अक्सर राजनीतिक दबाव और कड़े सरकारी नियमों के कारण अपनी स्वायत्तता खो देता है। विभागों में हर छोटे खर्च के लिए लंबी प्रक्रिया अपनानी पड़ती है, जो व्यापारिक प्रतिस्पर्धा के लिए बाधक है। इसके अलावा, बार-बार होने वाले राजनीतिक हस्तक्षेप से व्यावसायिक निर्णय प्रभावित होते हैं। यही कारण है कि रेलवे या बिजली जैसे उद्योगों के लिए लोक निगमों को विभागीय ढांचे की तुलना में अधिक श्रेष्ठ माना जाता है।

Click Here to Buy book on Amazon

में बदल जाते हैं। यह संगठन की आंतरिक कार्यप्रणाली को दर्शाता है जहाँ संसाधनों का प्रसंस्करण किया जाता है। थ्रूपुट की दक्षता ही अंततः संगठन द्वारा समाज को प्रदान किए जाने वाले उत्पादों या सेवाओं की गुणवत्ता और प्रभावशीलता को निर्धारित करती है।

40. (B) P-4, Q-1, R-2, S-3
संगठन के सिद्धांत प्रशासनिक दक्षता सुनिश्चित करने के लिए आधारभूत ढांचे का कार्य करते हैं। नियंत्रण का क्षेत्र अधीनस्थों की वह संख्या है जिसे एक अधिकारी कुशलतापूर्वक संभाल सकता है। पदसोपान ऊपर से नीचे की ओर अधिकार के प्रवाह को दर्शाता है, जबकि आदेश की एकता यह सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक कर्मचारी का केवल एक ही अधिकारी हो। लाइन और स्टाफ का सिद्धांत आदेश देने और विशेषज्ञ सलाह देने वाली इकाइयों के कार्यों को स्पष्ट रूप से पृथक करता है।

41. (D) संगठन के प्राथमिक उद्देश्यों को पूर्ण करना।
लाइन एजेंसियाँ किसी भी संगठन की रीढ़ होती हैं क्योंकि वे सीधे उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उत्तरदायी होती हैं जिनके लिए संगठन बना है। उदाहरण के लिए, शिक्षा विभाग में शिक्षक और स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर लाइन कर्मी हैं। उनके पास निर्णय लेने और आदेश जारी करने का प्रत्यक्ष अधिकार होता है। उनका कार्य परिणाम-उन्मुख होता है और वे सीधे जनता को सेवाएँ प्रदान करते हैं। स्टाफ एजेंसियाँ इन लाइन इकाइयों को केवल तकनीकी सहायता और परामर्श प्रदान करती हैं।

42. (B) आर्थिक मानव
सीमित तर्कसंगतता की अवधारणा शास्त्रीय अर्थशास्त्र के आर्थिक मानव की धारणा को चुनौती देती है। आर्थिक मानव के मॉडल के अनुसार, व्यक्ति सदैव अपनी उपयोगिता को अधिकतम करने के लिए पूर्णतः तर्कसंगत निर्णय लेता है। हर्बर्ट साइमन ने तर्क दिया कि वास्तविक जीवन में मनुष्यों के पास सूचनाएँ अधूरी होती हैं और उनकी मानसिक क्षमताएँ भी सीमित होती हैं। इसलिए, वे अधिकतम करने के बजाय संतोषजनक विकल्प चुनते हैं, जिसे प्रशासनिक मानव कहा जाता है। यह यथार्थवादी दृष्टिकोण है।

43. (C) स्विट्ज़रलैंड की संघीय परिषद
स्विट्ज़रलैंड की संघीय परिषद बहुल मुख्य कार्यपालिका का एक अद्वितीय उदाहरण है। इसमें सात सदस्य होते हैं जो सामूहिक रूप से राज्य के प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं। इनमें से कोई भी सदस्य अन्य सदस्यों से ऊपर नहीं होता और सभी के पास समान अधिकार होते हैं। परिषद का अध्यक्ष केवल औपचारिक उद्देश्यों के लिए चुना जाता है। यह प्रणाली शक्ति के केंद्रीकरण को रोकती है और निर्णय लेने की प्रक्रिया में विभिन्न राजनीतिक हितों और समूहों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करती है।

44. (D) कार्यात्मक विशेषीकरण और विशेषज्ञ अधिकार के कारण यह प्रायः अव्यावहारिक होता है।
आधुनिक और जटिल संगठनों में, एक कर्मचारी को प्रायः अपने प्रशासनिक वरिष्ठ के अलावा विभिन्न तकनीकी विशेषज्ञों से भी निर्देश प्राप्त करने पड़ते हैं। इस कारण आदेश की एकता का पारंपरिक सिद्धांत, जो कहता है कि केवल एक ही अधिकारी होना चाहिए, व्यावहारिक नहीं रह जाता है। उदाहरण के लिए, एक अस्पताल में नर्स को प्रशासनिक कार्यों के लिए प्रबंधक की और चिकित्सा कार्यों के लिए डॉक्टर की बात माननी पड़ती है। यह कार्यात्मक जटिलता इस सिद्धांत के कड़ाई से अनुपालन को कठिन बनाती है।

45. (A) राजनीति-प्रशासन द्विभाजन
राजनीति-प्रशासन द्विभाजन का सिद्धांत लोक प्रशासन के अध्ययन के प्रारंभिक काल का प्रमुख विचार है। यह मानता है कि राजनीति का कार्य केवल नीतियों और नियमों का निर्धारण करना है, जबकि प्रशासन का कार्य उन नीतियों का तकनीकी और निष्पक्ष कार्यान्वयन करना है। वुड्रो विल्सन जैसे समर्थकों का मानना था कि प्रशासन को राजनीति के बाहरी प्रभाव से मुक्त रखकर एक वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया जाना चाहिए ताकि शासन में कार्यकुशलता और मितव्ययिता में वृद्धि हो सके।

46. (B) सजातीयता
फ्रेड रिग्स के प्रिज्माटिक समाज के मॉडल में विषमता, औपचारिकतावाद और अतिव्यापन तीन प्रमुख विशेषताएँ हैं। यहाँ सजातीयता का अभाव होता है क्योंकि यह समाज संक्रमणकालीन होता है और इसमें आधुनिक एवं पारंपरिक मूल्यों का मिश्रण होता है। सजातीयता प्रायः पूरी तरह विकसित समाजों का लक्षण है जहाँ एकसमान नियम पाए जाते हैं। प्रिज्माटिक समाजों में विभिन्न प्रकार की प्रशासनिक प्रथाएँ एक साथ मौजूद रहती हैं, जो प्रशासन को जटिल और कभी-कभी विरोधाभासी बनाती हैं।

47. (C) हर्बर्ट साइमन
संतोषप्रद शब्द हर्बर्ट साइमन द्वारा गढ़ा गया था, जो उनके निर्णय-निर्माण सिद्धांत का एक केंद्रीय हिस्सा है। यह शब्द संतोषजनक और पर्याप्त का मिश्रण है। साइमन के अनुसार, चूँकि व्यक्ति के पास पूर्ण सूचना और असीमित समय नहीं होता, इसलिए वह तब तक विकल्पों की खोज करता है जब तक उसे अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने वाला विकल्प नहीं मिल जाता। यह दृष्टिकोण प्रशासनिक यथार्थवाद को दर्शाता है जहाँ सर्वोत्तम विकल्प के बजाय व्यवहार्य विकल्प चुना जाता है।

48. (D) कर्मचारियों की सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं।
मानव संबंध सिद्धांत ने इस विचार को स्थापित किया कि कर्मचारी केवल आर्थिक पुरस्कारों से प्रेरित नहीं होते, बल्कि उनके प्रदर्शन पर सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारकों का गहरा प्रभाव पड़ता है। इस सिद्धांत के अनुसार, कार्यस्थल पर मधुर व्यक्तिगत संबंध और प्रबंधन का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार

NODIA

104. (B) P-3, Q-1, R-2, S-4
संगठन के विभिन्न घटक इसकी कार्यप्रणाली को व्यवस्थित करते हैं। पदसोपान वरिष्ठ और अधीनस्थ के बीच अधिकार के संबंध को स्थापित करता है। नियंत्रण का क्षेत्र एक वरिष्ठ के अधीन काम करने वाले लोगों की संख्या को सीमित करता है ताकि प्रभावी पर्यवेक्षण बना रहे। स्टाफ का कार्य विशिष्ट सलाह देना है, जो लाइन अधिकारियों के काम को सरल बनाता है। विकेंद्रीकरण अधिकार के प्रसार को दर्शाता है, जिससे संगठन के निचले स्तर सशक्त होते हैं। ये सभी मिलकर एक संतुलित प्रशासनिक संरचना का निर्माण करते हैं।

105. (B) अपने राजनीतिक दल के नेता के रूप में कार्य करना।
मुख्य कार्यपालिका की राजनीतिक भूमिका अत्यंत प्रभावशाली होती है, क्योंकि वह प्रायः सत्ताधारी दल का शीर्ष नेता होता है। इस भूमिका में वह अपने दल की विचारधारा को आगे बढ़ाता है, चुनाव प्रचार का नेतृत्व करता है और राजनीतिक नियुक्तियों के माध्यम से अपनी स्थिति को मजबूत करता है। उसका राजनीतिक कद ही उसे सरकार चलाने के लिए आवश्यक समर्थन और वैधता प्रदान करता है। यह भूमिका उसे एक राजनेता के रूप में जनमत और विधायी एजेंडा को प्रभावित करने की शक्ति प्रदान करती है।

106. (A) आदेश की एकता एक अधीनस्थ से संबंधित है; निर्देशन एक योजना से संबंधित है।
आदेश की एकता का मुख्य केंद्र व्यक्ति होता है, जिसका अर्थ है कि एक कर्मचारी को केवल एक ही अधिकारी से निर्देश मिलने चाहिए। इसके विपरीत, निर्देशन की एकता का संबंध संगठन के उद्देश्यों से है, जिसका अर्थ है कि समान लक्ष्यों वाली गतिविधियों का एक ही प्रमुख और एक ही मास्टर प्लान होना चाहिए। आदेश की एकता अनुशासन सुनिश्चित करती है, जबकि निर्देशन की एकता प्रयासों में समन्वय और दिशा प्रदान करती है। ये दोनों सिद्धांत मिलकर संगठनात्मक भ्रम को कम करने में सहायक होते हैं।

107. (B) केवल 2 और 3
अनौपचारिक संगठन प्रबंधन द्वारा नहीं बनाया जाता, बल्कि यह कर्मचारियों के बीच सामाजिक अंतःक्रियाओं से स्वतः उत्पन्न होता है। यह समूह के सामाजिक मानदंडों और व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर चलता है। इसकी महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह औपचारिक लक्ष्यों का समर्थन भी कर सकता है और कभी-कभी उनके विपरीत भी जा सकता है। उदाहरण के लिए, एक अनौपचारिक समूह काम की गति बढ़ा भी सकता है या हड़ताल को बढ़ावा दे सकता है। कथन 1 गलत है क्योंकि यह सचेत रूप से बनाया गया ढाँचा नहीं है।

108. (C) प्रक्रिया-उन्मुख
पारंपरिक प्रशासन प्रायः नियमों, विनियमों और प्रक्रियाओं के कठोर पालन पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसके कारण कभी-कभी वास्तविक लक्ष्य गौण हो जाते हैं। इसके विपरीत, विकास प्रशासन परिणाम-उन्मुख होता है, जिसका मुख्य उद्देश्य समाज में सकारात्मक बदलाव लाना और निर्धारित विकास लक्ष्यों को समय पर पूरा करना है। यह प्रशासन केवल यह नहीं देखता कि काम कैसे किया गया, बल्कि यह देखता है कि काम का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। यह लचीलापन और उद्देश्यपरकता ही इसे पुरानी नौकरशाही से अलग बनाती है।

109. (C) जीव विज्ञान
लोक प्रशासन में व्यवस्था दृष्टिकोण जीव विज्ञान के सिद्धांतों से काफी प्रभावित है। जिस प्रकार एक जीवित शरीर के विभिन्न अंग आपस में जुड़े होते हैं और वातावरण के साथ अंतःक्रिया करते हैं, उसी प्रकार एक संगठन भी परस्पर निर्भर भागों का समूह है। लुडविग वॉन बर्टलान्फी जैसे वैज्ञानिकों के सामान्य व्यवस्था सिद्धांत ने प्रशासन को एक जैविक प्रणाली के रूप में देखने की प्रेरणा दी। यह विचार संगठन को केवल एक निर्जीव यंत्र के बजाय एक जीवित और विकासशील इकाई के रूप में समझने में मदद करता है।

110. (D) इसके कर्मचारियों को सामान्यतः मानक सिविल सेवा नियमों के अधीन सिविल सेवक माना जाता है।
लोक निगमों की एक प्रमुख विशेषता यह है कि उनके कर्मचारी सामान्यतः सरकारी सिविल सेवा के अंतर्गत नहीं आते हैं। निगम के पास अपनी स्वतंत्र भर्ती नीति, वेतन ढाँचा और सेवा शर्तें होती हैं। यह उन्हें सरकारी विभागों के सिविल सेवा नियमों की जटिलताओं से दूर रखकर अधिक व्यावसायिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। लोक निगम अपने कर्मचारियों को बाजार की प्रतिस्पर्धा के अनुसार नियुक्त कर सकते हैं। अतः यह कहना गलत है कि उनके कर्मचारियों को मानक सरकारी सिविल सेवक माना जाता है।

111. (D) अनौपचारिक संगठन
ग्रेपवाइन संचार का वह माध्यम है जो अनौपचारिक संगठनों में व्यापक रूप से पाया जाता है। इसमें सूचनाएँ किसी औपचारिक आदेश की श्रृंखला का पालन किए बिना, व्यक्तिगत संबंधों के माध्यम से बहुत तेजी से फैलती हैं। हालाँकि यह संचार का सबसे विश्वसनीय स्रोत नहीं होता, लेकिन यह कर्मचारियों की भावनाओं और संगठन के आंतरिक माहौल को समझने के लिए बहुत उपयोगी होता है। ग्रेपवाइन प्रायः तब सक्रिय होता है जब औपचारिक संचार चैनलों में पारदर्शिता की कमी होती है या कोई अनिश्चितता होती है।

112. (A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
जब एक प्रबंधक के पास बहुत कम अधीनस्थ होते हैं, तो वह उनके हर छोटे कार्य में हस्तक्षेप करने लगता है, जिसे सूक्ष्म-प्रबंधन कहा जाता है। इससे कर्मचारियों की स्वायत्तता और सृजनात्मकता समाप्त हो जाती है। इसके अलावा, नियंत्रण का संकीर्ण क्षेत्र प्रबंधन के कई स्तरों का निर्माण करता है, जिससे सूचनाओं के आदान-प्रदान में बहुत देरी होती है। यह कठोर नियंत्रण और नौकरशाही की जटिलता संगठन की गतिशीलता को कम कर देती है, जिससे निर्णय लेने की प्रक्रिया अत्यंत धीमी और बोझिल हो जाती है।

113. (C) मुख्य राजनयिक
मुख्य कार्यपालिका जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करती है, तो वह मुख्य राजनयिक की भूमिका

NODIA

आते हैं क्योंकि वे बाजार और समाज की बदलती मांगों के अनुसार खुद को ढालते रहते हैं। यह निरंतर अनुकूलन ही उनकी सफलता का आधार है।

150. (B) निचले स्तरों पर त्वरित निर्णय लेने की ओर ले जाता है और कनिष्ठ प्रबंधकों को प्रशिक्षित करता है।
विकेंद्रीकरण संगठन की कार्यक्षमता को कई तरह से बढ़ाता है। जब निर्णय लेने की शक्ति निचले स्तर के अधिकारियों को दी जाती है, तो फाइलें ऊपर भेजने में लगने वाला समय बचता है, जिससे काम तेजी से होता है। इसके अलावा, जब कनिष्ठ अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी जाती है, तो वे व्यावहारिक रूप से निर्णय लेना सीखते हैं और उनमें नेतृत्व के गुण विकसित होते हैं। यह व्यवस्था शीर्ष प्रबंधन के कार्यभार को भी कम करती है, जिससे वे केवल महत्वपूर्ण रणनीतिक विषयों पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर पाते हैं।

151. (C) उत्तरदायित्व का प्रसार और निष्क्रियता की संभावना।
बहुल कार्यपालिका में शक्ति कई सदस्यों के बीच समान रूप से बँटी होती है, जिससे यह खतरा बना रहता है कि किसी बड़ी असफलता की स्थिति में कोई भी व्यक्ति जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं होगा। चर्चाओं और असहमतियों के कारण निर्णय लेने की गति धीमी हो सकती है, जो संकट के समय घातक हो सकती है। उत्तरदायित्व के इस फैलाव से कभी-कभी प्रशासन में ढिलाई की प्रवृत्ति पैदा होती है। यह प्रणाली निरंकुशता को तो रोकती है, लेकिन इसके लिए उच्च स्तर के समन्वय की निरंतर आवश्यकता होती है।

152. (B) लूथर गुलिक
लूथर गुलिक ने 'पोसडकॉर्ब' शब्द के माध्यम से मुख्य कार्यपालिका के सात मूलभूत कार्यों को संक्षेप में प्रस्तुत किया था। इनमें योजना बनाना, संगठित करना, कर्मचारियों की नियुक्ति, निर्देशन, समन्वय, रिपोर्टिंग और बजट बनाना सम्मिलित हैं। गुलिक का मानना था कि किसी भी संगठन का प्रमुख इन्हीं सात गतिविधियों के माध्यम से प्रशासन पर अपना नियंत्रण रखता है और उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करता है। यद्यपि आधुनिक काल में इसकी आलोचना हुई है, फिर भी यह प्रशासनिक कार्यों को समझने के लिए उपयोगी रूपरेखा प्रदान करता है।

153. (B) स्टाफ एजेंसी
एक नगर योजना आयोग जो मेयर को केवल विशेषज्ञ सलाह और भविष्य की विकास योजनाओं का खाका तैयार करके देता है, एक स्टाफ एजेंसी के रूप में कार्य करता है। इसके पास नीतियों को सीधे लागू करने या नागरिकों को आदेश देने का कोई अधिकार नहीं होता। इसका मुख्य उद्देश्य मेयर को ऐसे तथ्य और विश्लेषण उपलब्ध कराना है जिससे वे बेहतर और दूरदर्शी निर्णय ले सकें। स्टाफ एजेंसियाँ ज्ञान की शक्ति पर आधारित होती हैं और संगठन की दीर्घकालिक योजना प्रक्रिया में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

154. (A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
अनौपचारिक संगठन केवल सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति ही नहीं करते, बल्कि वे नवाचार को भी बढ़ावा देते हैं क्योंकि वहाँ संचार का माहौल अधिक मुक्त और कम दबाव वाला होता है। कर्मचारी अनौपचारिक बातचीत के दौरान नए विचारों पर चर्चा कर सकते हैं जो औपचारिक बैठकों में नहीं आ पाते। इसके अलावा, अनौपचारिक चैनलों के माध्यम से सूचनाएं अत्यंत तीव्रता से फैलती हैं, जो कभी-कभी संकट के समय संगठन के लिए उपयोगी साबित होती हैं। यह लचीलापन संगठन की सृजनात्मकता बढ़ाने में योगदान देता है।

155. (A) रॉबर्ट मिशेल्स
रॉबर्ट मिशेल्स ने अल्पतंत्र का लौह नियम प्रतिपादित किया, जिसमें उन्होंने तर्क दिया कि कोई भी संगठन, चाहे वह कितना भी लोकतांत्रिक क्यों न हो, अंततः एक छोटे से समूह के नियंत्रण में आ ही जाता है। उनके अनुसार, संगठन की जटिलता और नेतृत्व की आवश्यकता के कारण सत्ता धीरे-धीरे कुछ ही लोगों के हाथों में केंद्रित हो जाती है। यह छोटा समूह संगठन के उद्देश्यों के बजाय अपनी स्वयं की सत्ता को बनाए रखने पर अधिक ध्यान देने लगता है, जो लोकतंत्र के लिए बड़ी चुनौती है।

156. (B) एक प्रशासनिक प्रणाली और उसके सामाजिक संदर्भ के बीच संबंधों को समझना।
लोक प्रशासन का पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण इस आधारभूत सत्य को स्वीकार करता है कि प्रशासन समाज से अलग कोई स्वतंत्र इकाई नहीं है। यह समाज की आर्थिक स्थिति, राजनीतिक विचारधारा और सांस्कृतिक मूल्यों से निरंतर प्रभावित होता रहता है। इस दृष्टिकोण की मुख्य चिंता यह है कि किस प्रकार ये बाहरी कारक प्रशासनिक व्यवहार और संरचना को आकार देते हैं। यह विद्वानों को यह समझने में मदद करता है कि क्यों एक ही प्रकार की प्रशासनिक नीति अलग-अलग देशों में बिल्कुल अलग परिणाम प्रदान करती है।

157. (C) आदेश की एकता
आदेश की एकता का सिद्धांत मानता है कि एक कर्मचारी का केवल एक ही अधिकारी होना चाहिए ताकि कोई भ्रम न हो। लेकिन कार्यात्मक फोरमैनशिप या मैट्रिक्स संरचना में एक कर्मचारी को विभिन्न कार्यों के लिए अलग-अलग विशेषज्ञों से निर्देश प्राप्त करने पड़ते हैं। यह आधुनिक संगठनों की बढ़ती जटिलता और विशेषज्ञता की आवश्यकता के कारण होता है। चूँकि एक व्यक्ति हर विषय का विशेषज्ञ नहीं हो सकता, इसलिए कर्मचारी को कई उच्चाधिकारियों की सलाह माननी पड़ती है, जो सीधे तौर पर आदेश की एकता का उल्लंघन है।

158. (A) केवल 1 और 2
मुख्य कार्यपालिका की प्राथमिक जिम्मेदारी सरकारी मशीनरी का सफल संचालन और नीतियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है। इसके लिए वह शीर्ष अधिकारियों की नियुक्ति करती है और विभागों के कार्यों का निरंतर पर्यवेक्षण करती है। कथन 3 गलत है क्योंकि कानूनी विवादों का अंतिम निर्णय करना न्यायपालिका का कार्य है, कार्यपालिका का

Downloaded from www.pdf.tube

122. (D) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।
पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण इस विचार का विरोध करता है कि एक देश का प्रशासनिक मॉडल दूसरे देश में बिना सोचे-समझे लगाया जा सकता है। फ्रेड रिग्स ने स्पष्ट किया था कि प्रशासन को उस समाज की विशिष्ट पारिस्थितिकी या परिवेश के अनुकूल होना चाहिए। विकसित देशों के मॉडल विकासशील देशों में इसलिए विफल हो जाते हैं क्योंकि वहाँ का सामाजिक ढाँचा अलग होता है। अतः कथन I गलत है क्योंकि अंधानुकरण सफल नहीं हो सकता। प्रशासन को सफल बनाने के लिए स्थानीय मूल्यों और आवश्यकताओं को समझना अनिवार्य है।

123. (D) हेनरी फेयोल
हेनरी फेयोल को प्रशासनिक प्रबंधन विचारधारा का जनक माना जाता है। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में प्रबंधन के 14 सिद्धांतों को प्रस्तुत किया, जो आज भी प्रबंधन शिक्षा का आधार हैं। उनके सिद्धांतों में कार्य विभाजन, अनुशासन, आदेश की एकता और पहल जैसे महत्वपूर्ण विषय सम्मिलित हैं। फेयोल ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रबंधन केवल व्यवसाय के लिए नहीं, बल्कि सरकार और अन्य सभी संगठनों के लिए आवश्यक है। उनके ये सिद्धांत संगठन में स्थिरता और दक्षता लाने के उद्देश्य से बनाए गए थे।

124. (D) गति, गोपनीयता और निर्णायक कार्रवाई।
परिषद या बोर्ड जैसे सामूहिक निकाय उन कार्यों के लिए अनुपयुक्त होते हैं जहाँ बहुत तेजी से निर्णय लेने या पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने की आवश्यकता होती है। चूँकि परिषद में कई सदस्य होते हैं, इसलिए चर्चा में बहुत समय लग सकता है और सूचनाओं के बाहर आने की संभावना अधिक रहती है। सैन्य अभियानों या संकटकालीन परिस्थितियों में, जहाँ एक कमान और तुरंत कार्रवाई की आवश्यकता होती है, वहाँ परिषद के बजाय एक एकल और सशक्त कार्यपालिका अधिक प्रभावी और परिणामोन्मुखी सिद्ध होती है।

125. (C) फीडबैक लूप
फीडबैक लूप व्यवस्था दृष्टिकोण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक संगठन अपने कार्यों के परिणामों के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। यदि परिणाम अपेक्षा के अनुरूप नहीं है, तो संगठन इस सूचना का उपयोग अपने इनपुट या प्रक्रियाओं में सुधार करने के लिए करता है। यह तंत्र संगठन को आत्म-सुधार और बाहरी वातावरण के साथ तालमेल बिठाने में सक्षम बनाता है। इसके बिना, कोई भी प्रणाली अपनी गलतियों को सुधारने और भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार होने में असमर्थ रहती है।

126. (C) अर्ध-न्यायिक शक्ति है
मुख्य कार्यपालिका द्वारा क्षमादान देना या दंड की अवधि कम करना एक अर्ध-न्यायिक शक्ति है। यद्यपि न्याय प्रदान करना न्यायालयों का मुख्य कार्य है, लेकिन संविधान कार्यपालिका को यह अधिकार देता है कि वह विशेष परिस्थितियों में न्यायिक निर्णयों की समीक्षा कर सके। यह शक्ति न्याय प्रणाली में एक अंतिम सुरक्षा वाल्व के रूप में कार्य करती है ताकि किसी भी संभावित न्यायिक त्रुटि को सुधारा जा सके। यह कार्यपालिका को शासन में न्याय और मानवीय दया के संतुलन को बनाए रखने का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है।

127. (D) नीति-निर्माण और नीति-निष्पादन
राजनीति-प्रशासन द्विभाजन का मूल विचार यह है कि राजनीति और प्रशासन दो अलग-अलग कार्यक्षेत्र हैं। राजनीति का मुख्य कार्य जनता की इच्छाओं को समझना और उनके आधार पर नीतियाँ बनाना है। प्रशासन का दायित्व उन नीतियों को बिना किसी राजनीतिक पक्षपात के कुशलतापूर्वक लागू करना है। इस सिद्धांत ने लोक प्रशासन को एक स्वतंत्र विषय बनाने में मदद की। हालाँकि आधुनिक युग में यह विभाजन धुंधला हो गया है क्योंकि प्रशासक भी अब नीति निर्धारण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

NODIA

128. (B) आदेश की एकता
आदेश की एकता का सिद्धांत कहता है कि एक कर्मचारी को केवल एक ही अधिकारी से निर्देश प्राप्त होने चाहिए। मैट्रिक्स संगठन में, एक कर्मचारी को एक ही समय में अपने स्थायी विभाग प्रमुख और एक अस्थायी प्रोजेक्ट मैनेजर दोनों की बात माननी पड़ती है। यह स्थिति दोहरा नियंत्रण पैदा करती है, जिससे कर्मचारी में भ्रम और कार्य के प्रति निष्ठा का संकट उत्पन्न हो सकता है। यह संरचना भले ही कार्यों में लचीलापन लाती है, लेकिन यह पारंपरिक पदसोपान और एकहरे कमान के नियमों को खुली चुनौती देती है।

129. (C) अनौपचारिक समूह मानदंडों का अस्तित्व जिन्होंने उत्पादन को प्रतिबंधित किया।
हाथोर्न प्रयोगों के अंतर्गत बैंक वायरिंग अध्ययन ने यह उजागर किया कि श्रमिक प्रबंधन के निर्धारित लक्ष्यों के बजाय अपने स्वयं के अनौपचारिक समूह नियमों का पालन करते हैं। समूह ने खुद ही तय कर रखा था कि कोई भी व्यक्ति बहुत अधिक काम करके दूसरों को दबाव में नहीं डालेगा। जो लोग बहुत अधिक काम करते थे, उन्हें समूह द्वारा हतोत्साहित किया जाता था। इस खोज ने सिद्ध किया कि अनौपचारिक सामाजिक दबाव उत्पादकता को नियंत्रित करने में औपचारिक प्रोत्साहन योजनाओं से कहीं अधिक शक्तिशाली हो सकते हैं।

130. (C) अनियोजित निर्णय-निर्माण
जब कोई अप्रत्याशित संकट जैसे कि डेटा उल्लंघन या साइबर हमला उत्पन्न होता है, तो इसके लिए लिए जाने वाले निर्णय अनियोजित होते हैं। चूँकि ऐसी घटनाओं के लिए कोई पूर्व-निर्धारित नियमावली उपलब्ध नहीं होती, इसलिए नेतृत्व को उस समय उपलब्ध सूचनाओं और अपने विवेक का उपयोग करके नई रणनीति बनानी पड़ती है। ये निर्णय अत्यंत तनावपूर्ण होते हैं और संगठन की साख को बचाने के लिए अनिवार्य होते हैं। इसमें जोखिम अधिक होता है और त्वरित एवं मौलिक सोच की निरंतर आवश्यकता बनी रहती है।

131. (B) मैक्स वेबर
मैक्स वेबर ने नौकरशाही का एक ऐसा आदर्श मॉडल प्रस्तुत किया जो पूर्णतः तार्किकता, निष्पक्षता और लिखित नियमों पर आधारित था। वेबर का मानना था कि आधुनिक समाजों के

रूप से सिद्ध नहीं हैं और अक्सर एक-दूसरे के विरोधी होते हैं। उदाहरण के लिए, पदसोपान दक्षता बढ़ाता है लेकिन संचार धीमा कर देता है। साइमन के अनुसार, ये सिद्धांत केवल सतही बातें हैं जो हर स्थिति में खरी नहीं उतरतीं। उन्होंने प्रशासन के अध्ययन में व्यवहारवादी और अधिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने की वकालत की थी।

187. (B) संसदीय प्रणाली
संसदीय प्रणाली की एक मुख्य विशेषता यह है कि कार्यपालिका और विधायिका के बीच शक्तियों का विलय होता है। प्रधानमंत्री, जो वास्तविक कार्यपालिका है, संसद का सदस्य होता है और संसद के प्रति ही उत्तरदायी रहता है। वह तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे निचले सदन का विश्वास प्राप्त है। यह प्रणाली सुनिश्चित करती है कि सरकार की नीतियों पर निरंतर विधायी नियंत्रण बना रहे। यह अध्यक्षीय प्रणाली से भिन्न है जहाँ राष्ट्रपति विधायिका का हिस्सा नहीं होता और उसकी शक्तियाँ पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं।

188. (B) line अधिकारी
लाइन और स्टाफ संगठन में, अंतिम निर्णय लेने और आदेश जारी करने का अधिकार केवल लाइन अधिकारियों के पास होता है। वे संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सीधे जिम्मेदार होते हैं। स्टाफ अधिकारियों का कार्य केवल विशेषज्ञों के रूप में सलाह देना और अनुसंधान करना है, लेकिन वे किसी लाइन कर्मचारी को कोई आदेश नहीं दे सकते। उत्तरदायित्व और अधिकार के इस स्पष्ट बँटवारे का उद्देश्य संगठन में कमान की अखंडता बनाए रखना है। यदि स्टाफ को भी आदेश देने की शक्ति मिल जाए, तो अनुशासन का संकट हो सकता है।

189. (D) 1, 2 और 3
एक आधुनिक मुख्य कार्यपालिका बहुआयामी भूमिकाएँ निभाती है। वह मुख्य राजनयिक के रूप में देश की विदेश नीति और अंतरराष्ट्रीय संबंधों का नेतृत्व करती है। कमांडर-इन-चीफ के रूप में वह राष्ट्र की सेनाओं का सर्वोच्च प्रमुख होती है और सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालती है। इसके अतिरिक्त, वह अपने राजनीतिक दल की नेता भी होती है, जिससे वह विधायिका और जनमत को प्रभावित कर पाती है। ये सभी भूमिकाएँ मिलकर उसे शासन की सबसे शक्तिशाली संस्था बनाती हैं, जिससे राष्ट्र का सुचारु संचालन सुनिश्चित होता है।

190. (C) निर्धारित मानदंडों और व्यावहारिक वास्तविकता के बीच एक महत्वपूर्ण विसंगति।
प्रिज्मीय समाज में औपचारिकतावाद का अर्थ है कि शासन व्यवस्था में नियम और कानून तो बहुत आधुनिक बनाए जाते हैं, लेकिन वास्तव में उन्हें लागू नहीं किया जाता। उदाहरण के लिए, समानता के कानून कागजों पर हो सकते हैं, लेकिन व्यवहार में भाई-भतीजावाद का बोलबाला रहता है। यह अंतर प्रशासन में पाखंड और अकुशलता पैदा करता है। रिग्स ने इसे विकासशील देशों की एक प्रमुख कमजोरी माना था जहाँ पश्चिमी नकल तो की जाती है, लेकिन आंतरिक सामाजिक और प्रशासनिक सुधारों की निरंतर उपेक्षा की जाती है।

191. (B) सरकारी नीति के एक प्रमुख, महत्वपूर्ण क्षेत्र का प्रशासन करना।
विभाग सरकार का सबसे बुनियादी और पुराना संगठनात्मक रूप है। प्रत्येक विभाग को शासन के एक विशिष्ट और महत्वपूर्ण कार्य, जैसे कि शिक्षा या रक्षा, का उत्तरदायित्व सौंपा जाता है। विभाग का नेतृत्व एक राजनीतिक मंत्री करता है, जिससे नीति निर्धारण और क्रियान्वयन में समन्वय बना रहता है। विभागों के माध्यम से सरकार अपनी प्राथमिकताओं को जनता तक पहुँचाती है और सार्वजनिक संसाधनों का प्रबंधन करती है। यह संरचना प्रत्यक्ष विधायी नियंत्रण और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सबसे प्रभावी मानी जाती है।

192. (C) यदि उचित रूप से प्रबंधित किया जाए, तो नवाचार की ओर ले जाने वाली एक सकारात्मक शक्ति हो सकता है।
मैरी पार्कर फॉलेट ने संघर्ष को केवल नकारात्मक रूप में देखने के बजाय उसे एक अवसर के रूप में देखा। उनकी रचनात्मक संघर्ष की अवधारणा का अर्थ है कि जब दो अलग-अलग विचार आपस में टकराते हैं, तो उनके बीच समन्वय के माध्यम से एक नया और बेहतर विचार जन्म ले सकता है। संघर्ष को दबाने के बजाय, दोनों पक्षों की चिंताओं को समझकर एक तीसरा समाधान खोजना चाहिए। यह दृष्टिकोण संगठन में टीम वर्क, नवाचार और आपसी समझ को बढ़ावा देने में अत्यंत प्रभावी है, जो प्रगति के लिए अनिवार्य है।

193. (D) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।
व्यवस्था दृष्टिकोण के बारे में कथन I गलत है क्योंकि यह दृष्टिकोण वास्तव में संगठन को एक खुली व्यवस्था के रूप में देखता है जो अपने वातावरण से निरंतर प्रभावित होती है। इसके विपरीत, कथन II बिल्कुल सही है क्योंकि पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण इस बात पर बल देता है कि एक प्रशासनिक प्रणाली और उसके बाहरी सामाजिक परिवेश के बीच गहरा संबंध होता है। ये दोनों ही आधुनिक दृष्टिकोण इस बात को स्वीकार करते हैं कि कोई भी संगठन बाहरी दुनिया से अलग होकर सफलतापूर्वक और लंबे समय तक कार्य नहीं कर सकता।

194. (B) राजनीति-प्रशासन द्विभाजन
राजनीति-प्रशासन द्विभाजन का मुख्य तर्क यह था कि प्रशासन एक व्यावसायिक क्षेत्र है, जिसे राजनीति की अनिश्चितता से दूर रखा जाना चाहिए। वुड्रो विल्सन जैसे विचारकों का मानना था कि यदि प्रशासन को राजनीति से अलग करके स्वतंत्र रूप से विकसित किया जाए, तो इसे एक विज्ञान बनाया जा सकता है जहाँ दक्षता के सार्वभौमिक नियम लागू होंगे। इस विचार ने लोक प्रशासन को एक निष्पक्ष और पेशेवर पहचान देने का प्रयास किया, जिससे सरकारी कार्यों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और व्यावसायिकता को निरंतर बढ़ावा मिला।

195. (B) अधीनस्थों की वह संख्या जिसे एक प्रबंधक प्रभावी ढंग से पर्यवेक्षित कर सकता है।
नियंत्रण का क्षेत्र प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जो एक प्रबंधक की प्रभावी पर्यवेक्षण क्षमता को परिभाषित करता है। यह इस विचार पर आधारित है कि एक व्यक्ति की समय और ध्यान केंद्रित करने की एक सीमा होती है। यदि

Click Here to Buy book on Amazon

और समूह की गतिशीलता जैसे विषयों का गहन विश्लेषण करता है। हर्बर्ट साइमन और चेस्टर बर्नार्ड जैसे विचारकों ने इस दृष्टिकोण को लोकप्रिय बनाया, जिससे प्रशासन को समझने के लिए समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के उपयोग का मार्ग प्रशस्त हुआ।

141. (C) पदसोपान का सिद्धांत
पदसोपान के सिद्धांत की पूरी इमारत वरिष्ठ और अधीनस्थ के बीच के औपचारिक संबंधों पर टिकी हुई है। यह व्यवस्था अधिकार का वितरण करती है और यह तय करती है कि कौन निर्देश देगा और कौन उनका पालन करेगा। यह संबंध ही संगठन में जवाबदेही की नींव रखता है। पदसोपान के माध्यम से ही कार्यों का प्रत्यायोजन संभव होता है, जिससे शीर्ष अधिकारी केवल महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान दे सकते हैं और अन्य कार्य अधीनस्थों को सौंप दिए जाते हैं। यह किसी भी बड़े संगठन की आधारभूत संरचना है।

142. (D) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।
लाइन और स्टाफ इकाइयों की भूमिकाएँ बिल्कुल अलग होती हैं। कथन I गलत है क्योंकि लाइन एजेंसियों का प्राथमिक कार्य संगठन के मुख्य उद्देश्यों को सीधे तौर पर पूरा करना है। स्टाफ एजेंसियों का कार्य मुख्य कार्यपालिका को विशेषज्ञ परामर्श, योजना और अनुसंधान के माध्यम से सहायता प्रदान करना है। स्टाफ इकाइयाँ पर्दे के पीछे रहकर काम करती हैं और लाइन इकाइयों को उनके कार्यों को बेहतर ढंग से करने के लिए आवश्यक ज्ञान उपलब्ध कराने में मदद करती हैं, जिससे संगठन की प्रभावशीलता बढ़ती है।

143. (C) मानव संबंध विचारधारा।
मानव संबंध विचारधारा ने इस विचार को स्थापित किया कि यदि प्रबंधन श्रमिकों की मानवीय भावनाओं का सम्मान करता है और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करता है, तो उनका मनोबल और उत्पादकता स्वतः बढ़ जाती है। इस विचारधारा के अनुसार, कार्यस्थल केवल एक आर्थिक क्षेत्र नहीं, बल्कि एक सामाजिक क्षेत्र भी है। एल्टन मेयो ने सिद्ध किया कि काम की अच्छी परिस्थितियों और बेहतर मानवीय व्यवहार से श्रमिकों में संगठन के प्रति वफादारी बढ़ती है, जो अंततः संगठन की समग्र सफलता और स्थिरता सुनिश्चित करती है।

144. (A) एक एकल व्यक्ति में अंतिम कार्यकारी प्राधिकार निहित होना।
एकल कार्यपालिका मॉडल में शासन की अंतिम जिम्मेदारी और शक्ति एक ही व्यक्ति के पास होती है, जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के मामले में है। यद्यपि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक कैबिनेट होती है, लेकिन अंतिम निर्णय लेने का अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास होता है। यह व्यवस्था नेतृत्व में एकता, निर्णयों में तीव्रता और नीतियों में निरंतरता सुनिश्चित करती है। संकट के समय ऐसी कार्यपालिका विशेष रूप से प्रभावी होती है क्योंकि इसमें उत्तरदायित्व का कोई भ्रम नहीं होता है।

145. (B) नियंत्रण का क्षेत्र
वी. ए. ग्रेक्युनास ने नियंत्रण के क्षेत्र से संबंधित एक गणितीय सिद्धांत प्रस्तुत किया था। उन्होंने यह तर्क दिया कि जैसे-जैसे एक प्रबंधक के अधीन अधीनस्थों की संख्या बढ़ती है, उनके बीच के आपसी संबंधों की संख्या ज्यामितीय रूप से बढ़ती जाती है। ग्रेक्युनास के अनुसार, एक प्रबंधक को न केवल व्यक्तिगत अधीनस्थों के साथ, बल्कि उनके समूहों के बीच होने वाली अंतःक्रियाओं को भी प्रबंधित करना पड़ता है। उनके इस विश्लेषण ने यह समझने में मदद की कि क्यों एक प्रबंधक केवल सीमित संख्या में लोगों को संभाल सकता है।

146. (A) P-3, Q-4, R-2, S-1
संगठनों के विभिन्न रूप उनकी विशिष्ट भूमिकाओं को दर्शाते हैं। विभाग पारंपरिक प्रशासनिक संरचनाएँ हैं जिनका नेतृत्व प्रायः एक राजनीतिक मंत्री करता है। लोक निगमों को व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए स्वायत्तता दी जाती है। लाइन एजेंसियाँ सीधे सरकारी सेवाओं को लागू करती हैं, जबकि स्टाफ एजेंसियाँ विशेषज्ञों के रूप में परामर्श और अनुसंधान का कार्य करती हैं। यह वर्गीकरण प्रशासन में कार्यों के स्पष्ट विभाजन और उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है, जिससे समग्र सरकारी तंत्र कुशलतापूर्वक कार्य कर सके।

147. (C) संतोषप्रद
हर्बर्ट साइमन ने तर्क दिया कि मनुष्य असीमित रूप से तर्कसंगत नहीं हो सकता क्योंकि उसके पास सूचनाओं की कमी और समय की सीमा होती है। इसलिए, किसी भी प्रशासनिक समस्या का समाधान खोजते समय, वह सभी संभावित विकल्पों का विश्लेषण करने के बजाय तब तक खोज जारी रखता है जब तक उसे पहला संतोषजनक और पर्याप्त विकल्प नहीं मिल जाता। इस प्रक्रिया को संतोषप्रद कहा जाता है। यह दृष्टिकोण आदर्श निर्णयों के बजाय व्यवहार्य निर्णयों पर बल देता है, जो वास्तविक दुनिया की प्रशासनिक चुनौतियों के लिए उपयुक्त है।

148. (B) संयुक्त राज्य अमेरिका
विकास प्रशासन की अवधारणा को मुख्य रूप से अमेरिकी विद्वानों, जैसे एडवर्ड वीडनर और फ्रेड रिग्स, द्वारा 1950 और 1960 के दशकों में लोकप्रिय बनाया गया था। यह विचार विशेष रूप से तृतीय विश्व के उन देशों के संदर्भ में विकसित हुआ जो नव स्वतंत्र हुए थे और जिन्हें त्वरित विकास की आवश्यकता थी। अमेरिकी लोक प्रशासन विद्वानों ने इन देशों की विशिष्ट प्रशासनिक चुनौतियों को समझने के लिए एक नए दृष्टिकोण की वकालत की। इस प्रयास ने लोक प्रशासन को अधिक वैश्विक और परिवर्तन-उन्मुख बनाने में मदद की।

149. (B) वातावरण के साथ इसकी अंतःक्रिया और विनिमय।
एक खुली व्यवस्था अपने बाहरी परिवेश के साथ लगातार सूचनाओं, संसाधनों और ऊर्जा का लेन-देन करती है। यह बंद व्यवस्था के विपरीत होती है, जो बाहरी दुनिया से कटी रहती है। खुली व्यवस्था वातावरण से प्राप्त प्रतिपुष्टि के आधार पर अपनी कार्यप्रणाली में बदलाव लाती है ताकि वह जीवित रह सके और प्रगति कर सके। आधुनिक संगठन इसी श्रेणी में

NODIA

कर्मचारियों के मनोबल और उनकी गुप्त चिंताओं को जानने का एक अच्छा माध्यम भी हो सकता है। यह संगठन के भीतर मानवीय संबंधों की जटिलता को दर्शाने वाला प्रमुख तत्व है।

168. (B) प्रबंधन के कई स्तर
एक लंबवत संगठनात्मक संरचना की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें शीर्ष नेतृत्व और निचले स्तर के कर्मचारियों के बीच प्रबंधन के कई पदसोपानिक स्तर होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रत्येक प्रबंधक के पास अधीनस्थों की एक सीमित संख्या होती है। इस संरचना में नियंत्रण बहुत कड़ा होता है, लेकिन संचार की गति धीमी हो जाती है क्योंकि हर सूचना को कई स्तरों से होकर गुजरना पड़ता है। यह संरचना प्रायः बड़े संगठनों में पाई जाती है जहाँ अनुशासन और सूक्ष्म पर्यवेक्षण पर अधिक जोर दिया जाता है।

169. (C) राजनीति-प्रशासन द्विभाजन
लोक प्रशासन के अध्ययन के प्रारंभिक काल में राजनीति-प्रशासन द्विभाजन का विचार सबसे प्रमुख था। वुड्रो विल्सन जैसे विचारकों ने यह तर्क दिया कि प्रशासन को राजनीति के दलगत प्रभाव से पूरी तरह मुक्त होना चाहिए। उनका मानना था कि नीतियां बनाना राजनीति का काम है और उन्हें बिना किसी भेदभाव के लागू करना प्रशासन का काम है। इस दृष्टिकोण ने लोक प्रशासन को एक तटस्थ और कुशल व्यावसायिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने में भूमिका निभाई, जिससे इसे एक अलग शैक्षणिक विषय की पहचान मिली।

170. (A) 4, 3, 1, 2
अमेरिकी राष्ट्रपतियों का कालक्रम अमेरिकी इतिहास के विभिन्न युगों को दर्शाता है। एंड्रयू जैक्सन 19वीं सदी के प्रारंभिक भाग में राष्ट्रपति थे। उनके बाद थियोडोर रूजवेल्ट 20वीं सदी के प्रारंभ में आए। वुड्रो विल्सन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान राष्ट्रपति थे, जिन्हें लोक प्रशासन के जनक के रूप में भी जाना जाता है। अंत में, फ्रैंकलिन डी. रूजवेल्ट ने महान मंदी और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान देश का नेतृत्व किया। यह अनुक्रम अमेरिकी प्रशासनिक व्यवस्था के क्रमिक विकास की एक महत्वपूर्ण कड़ी है।

171. (B) अव्यवस्था और क्षय की ओर बढ़ने की।
व्यवस्था दृष्टिकोण में एन्ट्रॉपी किसी भी व्यवस्था के स्वाभाविक रूप से समाप्त होने या अव्यवस्थित होने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। एक बंद व्यवस्था जो बाहरी वातावरण से ऊर्जा या सूचना प्राप्त नहीं करती, वह धीरे-धीरे अपनी कार्यक्षमता खो देती है और अंततः नष्ट हो जाती है। संगठनों के संदर्भ में, एन्ट्रॉपी का अर्थ है नवाचार की कमी और बाहरी परिवर्तनों के प्रति संवेदनहीनता। इससे बचने के लिए संगठनों को निरंतर नई ऊर्जा और संसाधनों के विनिमय की आवश्यकता होती है ताकि वे निरंतरता बनाए रख सकें।

172. (B) प्रशासनिक नियंत्रण और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना।
मुख्य कार्यपालिका के पास अधिकारियों की नियुक्ति और उन्हें हटाने की जो शक्ति होती है, वह प्रशासनिक अनुशासन बनाए रखने का सबसे प्रभावी उपकरण है। इस शक्ति के माध्यम से वह यह सुनिश्चित करती है कि सभी विभाग उसकी नीतियों का निष्ठापूर्वक पालन करें। जब अधिकारियों को पता होता है कि वे अपने पद के लिए सीधे मुख्य कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी हैं, तो वे अधिक सतर्क और कुशल रहते हैं। यह प्रक्रिया सरकार के विभिन्न अंगों के बीच समन्वय स्थापित करने और प्रशासनिक जवाबदेही तय करने में सहायक है।

173. (C) विकासशील देश
फ्रेड रिग्स का प्रिज्माटिक-साला मॉडल विशेष रूप से विकासशील देशों की प्रशासनिक वास्तविकताओं को समझने के लिए तैयार किया गया था। रिग्स ने महसूस किया कि इन देशों में पश्चिमी देशों के प्रशासनिक मॉडल सीधे लागू नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ के सामाजिक और आर्थिक हालात बहुत भिन्न हैं। प्रिज्माटिक मॉडल उन समाजों को दर्शाता है जो परंपरा से आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं। यह मॉडल बताता है कि कैसे इन देशों में आधुनिक नियम और पुरानी प्रथाएँ एक साथ मिलकर एक अनोखी प्रशासनिक संस्कृति का निर्माण करती हैं।

174. (D) वे अनौपचारिक समूहों की भूमिका पर अत्यधिक बल देते हैं।
शास्त्रीय संगठन सिद्धांतों की सबसे बड़ी आलोचना ही यह है कि वे अनौपचारिक समूहों और मानवीय भावनाओं की उपेक्षा करते हैं। ये सिद्धांत केवल औपचारिक संरचना और नियमों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हर्बर्ट साइमन ने इन्हें कहावतें कहकर इनकी वैज्ञानिकता पर प्रश्न उठाए थे क्योंकि ये अक्सर विरोधाभासी होते हैं। अतः, विकल्प (D) गलत है क्योंकि अनौपचारिक समूहों पर बल देना मानव संबंध सिद्धांत की विशेषता है। शास्त्रीय विचारक तो संगठन को केवल एक निर्जीव मशीन की तरह देखते थे, जो अपूर्ण दृष्टिकोण है।

175. (B) केंद्रीय नियंत्रण या स्टाफ एजेंसी
लोक सेवा आयोग एक स्टाफ एजेंसी के रूप में कार्य करता है क्योंकि इसका मुख्य कार्य सरकार को भर्ती और अनुशासनात्मक मामलों में विशेषज्ञ सलाह प्रदान करना है। यह सीधे सरकारी योजनाओं को लागू नहीं करता, बल्कि यह सुनिश्चित करता है कि प्रशासन को कुशल और योग्य कर्मचारी उपलब्ध हों। अपनी विशेषज्ञता और निष्पक्षता के माध्यम से यह शासन की गुणवत्ता सुधारने में मदद करता है। यह सरकार के भीतर योग्यता-आधारित प्रणाली को बनाए रखने का उत्तरदायित्व निभाता है, जिससे प्रशासन में पारदर्शिता बनी रहती है।

176. (B) P-3, Q-2, R-1, S-4
लोक प्रशासन के विचारकों ने विभिन्न महत्वपूर्ण अवधारणाएं प्रस्तुत की हैं। हर्बर्ट साइमन को सीमित तर्कसंगतता के लिए जाना जाता है, जो प्रशासनिक निर्णयों की सीमाओं को दर्शाता है। फ्रेड रिग्स ने प्रशासन की पारिस्थितिकी पर ध्यान केंद्रित किया, जिससे वातावरण के प्रभाव को समझा जा सके। एल्टन मेयो ने हाथोर्न प्रभाव के माध्यम से मानवीय संबंधों के महत्व को सिद्ध किया। चेस्टर बर्नार्ड ने कार्यपालिका के कार्य का विश्लेषण करते हुए संगठन को एक सहकारी सामाजिक प्रणाली के रूप में परिभाषित किया, जो अत्यंत प्रभावशाली है।

Downloaded from www.pdf.tube

नहीं। कार्यपालिका न्यायपालिका के निर्णयों को लागू करने में सहायता करती है, लेकिन वह स्वयं अंतिम अदालत नहीं होती। प्रशासन का निर्देशन और प्रबंधन ही उसके वास्तविक कार्यकारी उत्तरदायित्व हैं।

159. (C) बहु-कार्यात्मक
रिग्स के अनुसार, एक संग्लन समाज में संरचनाएँ बहु-कार्यात्मक होती हैं, जिसका अर्थ है कि एक ही संस्था कई तरह के अलग-अलग कार्य करती है। यहाँ समाज में श्रम का कोई विशेष विभाजन नहीं होता। उदाहरण के लिए, एक मुखिया ही न्याय भी करता है, कर भी वसूलता है और धार्मिक अनुष्ठान भी संपन्न कराता है। ऐसी व्यवस्था में आधुनिक प्रशासनिक विभागों जैसा कोई स्पष्ट अंतर नहीं पाया जाता है। यह प्रारंभिक और पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था का एक बुनियादी लक्षण है जो सरलता पर आधारित है।

160. (A) अग्निशमन विभाग
नगर प्रशासन में अग्निशमन विभाग एक लाइन इकाई का उदाहरण है क्योंकि यह विभाग सीधे जनता को सुरक्षा प्रदान करने के प्राथमिक उद्देश्य को पूरा करता है। लाइन इकाइयाँ वे होती हैं जो संकट की स्थिति में सीधे कार्रवाई करती हैं और नागरिकों के जीवन की रक्षा के लिए जिम्मेदार होती हैं। इसके विपरीत, वित्त या मानव संसाधन विभाग स्टाफ इकाइयों के रूप में कार्य करते हैं, जो केवल मुख्य विभागों को आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराते हैं ताकि वे अपना कार्य कुशलतापूर्वक और बिना बाधा के कर सकें।

161. (B) सर्वोत्तम संगठनात्मक संरचना विभिन्न स्थितिजन्य कारकों पर निर्भर करती है।
आकस्मिकता सिद्धांत का मुख्य तर्क यह है कि प्रबंधन का कोई भी सर्वोत्तम तरीका नहीं है जो हर परिस्थिति में काम करे। एक संगठन की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसकी संरचना उस समय के वातावरण, उपलब्ध तकनीक और कार्य की प्रकृति के साथ कितनी बेहतर तरीके से मेल खाती है। प्रबंधकों को किसी एक सिद्धांत पर अडिग रहने के बजाय स्थिति के अनुसार अपनी कार्यशैली बदलनी चाहिए। यह दृष्टिकोण संगठन के लचीलेपन पर बल देता है, जिससे अनिश्चित चुनौतियों का सामना करना सरल होता है।

162. (A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण दोनों के अपने विशिष्ट लाभ हैं। केंद्रीकरण आपातकालीन स्थितियों में बहुत उपयोगी होता है क्योंकि शीर्ष स्तर पर शक्ति होने से निर्णय बिना किसी देरी के लिए जा सकते हैं। दूसरी ओर, विकेंद्रीकरण कर्मचारियों को अधिक स्वायत्तता और जिम्मेदारी देकर उन्हें सशक्त बनाता है। जब कर्मचारी खुद निर्णय लेते हैं, तो उनमें आत्मविश्वास आता है और वे कार्य के प्रति अधिक समर्पित महसूस करते हैं। एक प्रभावी संगठन वही है जो इन दोनों प्रणालियों के बीच एक कुशल संतुलन बनाए रखता है।

163. (C) विकास प्रशासन कार्यक्रमों का प्रशासन है; प्रशासनिक विकास क्षमता का निर्माण है।
विकास प्रशासन मुख्य रूप से सामाजिक-आर्थिक प्रगति के लिए बनाई गई विशिष्ट परियोजनाओं और कार्यक्रमों को लागू करने से संबंधित है। इसके विपरीत, प्रशासनिक विकास का अर्थ स्वयं प्रशासनिक तंत्र की कार्यक्षमता और संरचना में सुधार करना है ताकि वह विकास की चुनौतियों का सामना कर सके। संक्षेप में, विकास प्रशासन का लक्ष्य बाहरी समाज का विकास है, जबकि प्रशासनिक विकास का लक्ष्य आंतरिक संस्थागत सुधार है। ये दोनों प्रक्रियाएँ एक-दूसरे की पूरक हैं क्योंकि कुशल प्रशासन के बिना विकास संभव नहीं है।

164. (A) लाभ अधिकतमकरण
संतोषप्रद की अवधारणा हर्बर्ट साइमन ने दी थी, जो शास्त्रीय अर्थशास्त्र के इस विचार को नकारती है कि मनुष्य हमेशा अपना लाभ अधिकतम करने वाला सर्वश्रेष्ठ विकल्प ही चुनता है। साइमन के अनुसार, मानवीय और प्रशासनिक सीमाओं के कारण व्यक्ति केवल पर्याप्त या संतोषजनक विकल्प ही खोज पाता है। यह वास्तविकता के अधिक निकट है क्योंकि असीमित संसाधनों और सूचनाओं के अभाव में सर्वश्रेष्ठ विकल्प तक पहुँचना प्रायः असंभव होता है। अतः प्रशासक इष्टतम के बजाय व्यवहार्य समाधानों पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं।

NODIA

165. (D) नाममात्र की कार्यपालिका
भारत का राष्ट्रपति संविधान के तहत राज्य का सर्वोच्च प्रमुख होता है, लेकिन वह नाममात्र की कार्यपालिका का एक विशिष्ट उदाहरण है। राष्ट्रपति की अधिकांश शक्तियों का वास्तविक प्रयोग प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाला मंत्रिमंडल करता है। राष्ट्रपति का पद गरिमा और राष्ट्र की एकता का प्रतीक है। उनके नाम पर सभी सरकारी कार्य किए जाते हैं, लेकिन वे स्वतंत्र रूप से नीतिगत निर्णय नहीं लेते। संसदीय लोकतंत्र में यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि वास्तविक शक्ति उन लोगों के पास रहे जो जनता के प्रति जवाबदेह हैं।

166. (B) लोक निगम
एक सरकारी रेलवे प्रणाली जो व्यावसायिक सिद्धांतों पर आधारित है, उसे लोक निगम के रूप में संगठित करना सबसे श्रेष्ठ है। लोक निगम को सरकारी विभागों की तुलना में अधिक वित्तीय और प्रशासनिक स्वायत्तता प्राप्त होती है, जिससे वह बाजार की आवश्यकताओं के अनुसार तेजी से निर्णय ले सकता है। उसे बजट के नियमों में छूट मिलती है, जो व्यावसायिक लाभप्रदता के लिए आवश्यक है। यह मॉडल जनहित की रक्षा करते हुए संगठन को एक निजी कंपनी की तरह कुशल और प्रतिस्पर्धी बनाने में सहायता करता है।

167. (B) ग्रेपवाइन
ग्रेपवाइन संचार का एक अनौपचारिक मार्ग है जो किसी भी संगठन के कर्मचारियों के बीच स्वतः विकसित हो जाता है। इसमें सूचनाएँ किसी पदसोपानिक श्रृंखला का पालन नहीं करतीं और बहुत तेजी से फैलती हैं। यह प्रायः गपशप या अनौपचारिक चर्चाओं के माध्यम से संचालित होता है। यद्यपि प्रबंधक इसे कभी-कभी हानिकारक मान सकते हैं, लेकिन यह

प्रबंधन के लिए नौकरशाही ही एकमात्र कुशल और तकनीकी रूप से श्रेष्ठ माध्यम है। उनके मॉडल में योग्यता पर आधारित चयन, कार्यों का स्पष्ट विभाजन और पदसोपान की व्यवस्था प्रमुख थी। वेबर ने इसे एक मशीन की तरह सटीक माना था जो व्यक्तिगत भावनाओं से मुक्त होकर शासन के लक्ष्यों को पूर्ण दक्षता से प्राप्त करती है।

132. (A) केवल 1 और 2
मैक्स वेबर की नौकरशाही में पदसोपान और कठोर नियमों का होना अनिवार्य है ताकि कार्यों में निरंतरता बनी रहे। पदसोपान अधिकार की एक श्रृंखला बनाता है, जबकि नियम निष्पक्षता सुनिश्चित करते हैं। कथन 3 गलत है क्योंकि वेबर के अनुसार, चयन और पदोन्नति केवल योग्यता और तकनीकी कौशल के आधार पर होनी चाहिए, न कि व्यक्तिगत पक्षपात के आधार पर। यह व्यवस्था नौकरशाही को अधिक पेशेवर बनाती है और सार्वजनिक कार्यों में पारदर्शिता एवं न्याय सुनिश्चित करने का निरंतर प्रयास करती है।

133. (B) संगठन को उसके वातावरण से पृथक करने वाली रेखा।
व्यवस्था दृष्टिकोण में, व्यवस्था सीमा वह काल्पनिक रेखा है जो संगठन के आंतरिक ढांचे और उसके बाहरी वातावरण के बीच के अंतर को स्पष्ट करती है। यह सीमा यह निर्धारित करती है कि कौन से तत्व संगठन के नियंत्रण में हैं और कौन से बाहरी हैं। सीमाएँ पूरी तरह अभेद्य नहीं होतीं; वे सूचना और ऊर्जा के विनिमय की अनुमति देती हैं। एक संगठन की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसकी सीमाएँ कितनी सक्रिय हैं और वह अपने वातावरण के साथ कितनी कुशलता से अंतःक्रिया कर रहा है।

134. (A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
विकास प्रशासन का कार्य क्षेत्र बहुत व्यापक है क्योंकि इसे समाज की मूलभूत समस्याओं को हल करना होता है। इसके लिए ऐसे प्रशासकों की आवश्यकता होती है जो केवल कागजी नियमों तक सीमित न रहें, बल्कि नई चुनौतियों के लिए नए समाधान खोज सकें। एक उद्यमी प्रशासक संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करता है और सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए जोखिम उठाता है। चूँकि विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसलिए इसके सफल कार्यान्वयन के लिए रचनात्मकता और दूरदर्शिता अत्यंत अनिवार्य गुण माने जाते हैं।

135. (C) विकेंद्रीकरण
विकेंद्रीकरण एक ऐसी प्रशासनिक रणनीति है जिसमें अधिकार का हस्तांतरण पदसोपान के शीर्ष से निचले स्तर के अधिकारियों को किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य निचले स्तरों को सशक्त बनाना और उन्हें अपने क्षेत्र की समस्याओं पर स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम बनाना है। यह प्रक्रिया शासन को जनता के करीब लाती है और प्रशासनिक बोझ को कम करती है। विकेंद्रीकरण से न केवल संगठन के लचीलेपन में वृद्धि होती है, बल्कि यह कनिष्ठ कर्मचारियों के भीतर जिम्मेदारी और नेतृत्व की भावना विकसित करने में सहायक होता है।

136. (D) पद में राज्य का प्रमुख होती है लेकिन बहुत कम वास्तविक शक्ति का प्रयोग करती है।
नाममात्र की कार्यपालिका वह पद है जिसके पास सैद्धांतिक रूप से तो बहुत सी शक्तियाँ होती हैं, लेकिन व्यवहार में वह उन शक्तियों का प्रयोग केवल वास्तविक कार्यपालिका की सलाह पर ही करता है। भारत के राष्ट्रपति इसके प्रमुख उदाहरण हैं। यह पद मुख्य रूप से राष्ट्र की एकता और निरंतरता का प्रतीक होता है। नाममात्र की कार्यपालिका औपचारिक समारोहों की अध्यक्षता करती है, जबकि शासन चलाने की वास्तविक जिम्मेदारी निर्वाचित सरकार के पास सुरक्षित रहती है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप है।

137. (D) व्यावसायिक संचालन में उच्च स्तर का लचीलापन और गति।
सरकारी विभागों को उनके कठोर नियमों और बजटीय सीमाओं के कारण व्यावसायिक रूप से बहुत लचीला नहीं माना जाता। विभागों में निर्णय लेने की प्रक्रिया कई स्तरों से गुजरती है, जिससे गति धीमी हो जाती है। यह प्रणाली उन कार्यों के लिए उपयुक्त है जहाँ अत्यधिक उत्तरदायित्व और सरकारी नियंत्रण की आवश्यकता होती है। व्यावसायिक या औद्योगिक कार्यों के लिए, जहाँ त्वरित निर्णय और बाजार के अनुसार बदलाव की जरूरत होती है, विभाग के बजाय लोक निगम या सार्वजनिक उपक्रम अधिक प्रभावी सिद्ध होते हैं।

138. (B) वैज्ञानिक प्रबंधन
फ्रेडरिक टेलर द्वारा विकसित वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत उत्पादकता बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि खोजने पर केंद्रित था। इसके लिए उन्होंने समय और गति का गहन अध्ययन किया ताकि कार्यों में लगने वाले अनावश्यक प्रयासों को कम किया जा सके। इस सिद्धांत ने कार्य के मानकीकरण और श्रमिकों के वैज्ञानिक प्रशिक्षण पर बल दिया। इसका उद्देश्य प्रबंधन और श्रमिकों के बीच सहयोग बढ़ाकर औद्योगिक उत्पादन को अधिकतम करना था। टेलर के इन विचारों ने आधुनिक कारखानों की कार्यप्रणाली को मौलिक रूप से प्रभावित किया।

139. (C) पदसोपान
सोपानिक सिद्धांत संगठन के उस ढांचे को संदर्भित करता है जहाँ अधिकार और उत्तरदायित्व की एक स्पष्ट श्रृंखला ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होती है। इसे प्रायः एक पिरामिड की तरह देखा जाता है जिसमें शीर्ष पर एक सर्वोच्च अधिकारी होता है और नीचे क्रमिक रूप से अन्य कर्मचारी होते हैं। यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि संगठन में आदेशों का प्रवाह व्यवस्थित हो और प्रत्येक व्यक्ति को पता हो कि वह किसके प्रति उत्तरदायी है। यह संरचना अनुशासन बनाए रखने और व्यवस्थित संचार के लिए महत्वपूर्ण है।

140. (B) व्यवहारवादी दृष्टिकोण
व्यवहारवादी दृष्टिकोण ने प्रशासनिक अध्ययन में मनुष्यों की वास्तविक कार्यशैली और उनके मनोविज्ञान पर ध्यान केंद्रित किया। यह मानता है कि औपचारिक नियमों से अधिक महत्वपूर्ण वह तरीका है जिससे व्यक्ति संगठन के भीतर एक-दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं। यह दृष्टिकोण प्रेरणा, नेतृत्व

Click Here to Buy book on Amazon

177. (D) उपर्युक्त सभी।
किसी संगठन में केंद्रीकरण या विकेंद्रीकरण का निर्णय कई महत्वपूर्ण कारकों पर आधारित होता है। बड़े और जटिल संगठनों में समन्वय के लिए विकेंद्रीकरण की आवश्यकता होती है। यदि अधीनस्थ अनुभवी और सक्षम हैं, तो उन्हें अधिक अधिकार दिए जा सकते हैं। इसी प्रकार, यदि पूरे देश में एकसमान नीति की आवश्यकता हो, तो केंद्रीकरण को प्राथमिकता दी जाती है। एक कुशल प्रशासक इन सभी परिस्थितियों का मूल्यांकन करके ही अधिकार के वितरण का सही स्वरूप तय करता है ताकि उद्देश्यों की प्राप्ति सुगमता से हो सके।

178. (B) नीति बनाना, देखरेख प्रदान करना और हितों का प्रतिनिधित्व करना।
बोर्ड या परिषद एक सामूहिक निर्णय लेने वाला निकाय होता है। इसका प्राथमिक कार्य संगठन की दीर्घकालिक नीतियों और दिशा-निर्देशों को तय करना है। यह कार्यपालिका के कार्यों की देखरेख करता है ताकि वे निर्धारित लक्ष्यों से न भटकें। इसके अलावा, परिषद में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को शामिल किया जाता है ताकि निर्णय प्रक्रिया में विविधता सुनिश्चित हो सके। यह व्यक्तिगत मनमानी को रोकने और अधिक संतुलित निर्णय लेने का एक महत्वपूर्ण संस्थागत माध्यम है, जो आधुनिक संगठनों के लिए अत्यंत आवश्यक है।

179. (C) सशस्त्र बल
मुख्य कार्यपालिका की कमांडर-इन-चीफ के रूप में भूमिका उसे राष्ट्र के सभी सैन्य बलों पर सर्वोच्च अधिकार प्रदान करती है। वह युद्ध की घोषणा करने, शांति संधियों पर निर्णय लेने और राष्ट्रीय सुरक्षा की रणनीतियाँ बनाने के लिए जिम्मेदार होती है। यह शक्ति नागरिक शासन की सेना पर सर्वोच्चता को सुनिश्चित करती है, जो लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है। इस भूमिका के माध्यम से मुख्य कार्यपालिका राष्ट्र की सीमाओं की रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के लिए अंतिम रूप से जवाबदेह होती है, जो अत्यंत महत्वपूर्ण है।

180. (C) एक नियोजित निर्णय
नियोजित निर्णय वे होते हैं जो दैनिक और नियमित आधार पर लिए जाते हैं। जब कार्यालय में पेन जैसी सामान्य सामग्री कम हो जाती है, तो उन्हें दोबारा मंगवाने के लिए किसी विशेष विश्लेषण की आवश्यकता नहीं होती। इसके लिए संगठन में पहले से ही एक निश्चित प्रक्रिया या नियमावली होती है। यह एक दोहराव वाला कार्य है जिसे निचले स्तर के कर्मचारी आसानी से निपटा सकते हैं। ऐसे निर्णयों से समय की बचत होती है और संगठन का दैनिक कार्य सुचारु रूप से चलता रहता है, जिससे दक्षता बनी रहती है।

181. (A) एक सहकारी सामाजिक प्रणाली के रूप में संगठन।
चेस्टर बर्नार्ड ने संगठन को केवल नियमों का समूह नहीं माना, बल्कि उसे व्यक्तियों के बीच सहयोग की एक जीवंत प्रणाली के रूप में देखा। उनका तर्क था कि एक संगठन तभी सफल हो सकता है जब उसके सदस्य स्वेच्छा से सामूहिक उद्देश्यों के लिए अपना योगदान दें। कार्यपालिका की असली चुनौती इसी सहयोग को प्राप्त करना और बनाए रखना है। बर्नार्ड ने मानवीय प्रेरणा और उदासीनता के क्षेत्र जैसे विचारों के माध्यम से यह समझाया कि संगठन किस प्रकार एक सामाजिक इकाई के रूप में कार्य करते हैं।

182. (A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
लोक निगमों को वित्तीय स्वायत्तता देने के पीछे मुख्य तर्क यह है कि वे बाजार की चुनौतियों का सामना एक निजी कंपनी की तरह तेजी से कर सकें। सरकारी विभागों के कठोर वित्तीय नियम व्यावसायिक विकास में बाधक बन सकते हैं। लोक निगमों को अपने स्वयं के संसाधन जुटाने और निवेश करने की स्वतंत्रता होती है। यह लचीलापन उन्हें अधिक प्रतिस्पर्धी और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए आवश्यक है। यही कारण है कि लाभ कमाने वाले सरकारी उपक्रमों के लिए निगम का स्वायत्त ढाँचा अपनाया जाता है।

183. (C) सरकार और Civil सेवा
लोक प्रशासन के अध्ययन की शुरुआत 19वीं सदी के उत्तरार्ध में सरकारी कामकाज और नागरिक सेवाओं में सुधार लाने के उद्देश्य से हुई थी। उस समय भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए प्रशासन को एक वैज्ञानिक और तटस्थ रूप देने की आवश्यकता महसूस की गई। वुड्रो विल्सन जैसे विद्वानों ने तर्क दिया कि सरकार को केवल यह नहीं जानना चाहिए कि नीतियाँ क्या हैं, बल्कि यह भी कि उन्हें सफलतापूर्वक कैसे लागू किया जाए। इस प्रकार, सरकारी मशीनरी और सिविल सेवा को अधिक उत्तरदायी बनाना ही इस विषय का आधार रहा है।

184. (B) एक ही संरचना कई कार्य करती है।
रिग्स के पारिस्थितिकीय मॉडल में बहु-कार्यात्मकता उस स्थिति को दर्शाती है जहाँ समाज के कार्यों का स्पष्ट विभाजन नहीं हुआ होता। एक ही प्रशासनिक इकाई या सामाजिक संस्था कई तरह के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कार्यों को अंजाम देती है। यह लक्षण विशेष रूप से संग्लन या विकासशील प्रिज्मीय समाजों में पाया जाता है जहाँ विशेषज्ञता का अभाव होता है। जैसे-जैसे समाज आधुनिक होता जाता है, संरचनाएं विशिष्ट होती जाती हैं और बहु-कार्यात्मकता का स्थान कार्यात्मक विशेषीकरण ले लेता है, जो विकास का सूचक है।

185. (A) एक विस्तृत क्षेत्र और कुछ पदसोपानिक स्तर।
सपाट संगठनात्मक संरचना में एक प्रबंधक के पास काम करने वाले अधीनस्थों की संख्या बहुत अधिक होती है, जिसे नियंत्रण का विस्तृत क्षेत्र कहा जाता है। इस व्यवस्था में ऊपर से नीचे तक प्रबंधन के बहुत कम स्तर होते हैं। इसके कारण संगठन में सूचनाओं का आदान-प्रदान बहुत तेजी से होता है और जटिलता कम होती है। यह संरचना कर्मचारियों के बीच अधिक संवाद और स्वायत्तता को बढ़ावा देती है, जिससे निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज होती है। यह आधुनिक कंपनियों में काफी लोकप्रिय है जो लचीलापन चाहती हैं।

186. (C) कहावतें
हर्बर्ट साइमन ने लोक प्रशासन के शास्त्रीय सिद्धांतों, जैसे आदेश की एकता या नियंत्रण का क्षेत्र, को कहावतें कहकर उनकी कड़ी आलोचना की। उनका तर्क था कि ये सिद्धांत वैज्ञानिक

Downloaded from www.pdf.tube

निभाती है। इस जिम्मेदारी के तहत वह अन्य देशों के साथ संधियों पर हस्ताक्षर करती है, विदेशी राष्ट्राध्यक्षों से वार्ता करती है और देश की विदेश नीति का मार्गदर्शन करती है। वह विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति भी करती है। यह भूमिका राष्ट्र की सुरक्षा और वैश्विक मंच पर उसकी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह कार्यपालिका को अंतरराष्ट्रीय संबंधों की एक निर्णायक शक्ति बनाता है।

114. (C) प्रिज्मीय समाज
फ्रेड रिग्स ने प्रिज्मीय समाज की प्रशासनिक व्यवस्था को परिभाषित करने के लिए साला शब्द का उपयोग किया है। साला एक ऐसा कार्यालय है जहाँ आधुनिक नियम तो मौजूद होते हैं, लेकिन उनका कार्यान्वयन पुराने पारंपरिक मूल्यों से गहराई से प्रभावित होता है। यहाँ भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद और नियमों की अनदेखी सामान्य होती है। यह मॉडल विशेष रूप से उन विकासशील देशों के लिए बनाया गया था जो आधुनिक प्रशासन अपनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जिनकी सामाजिक जड़ें पुरानी परंपराओं और रीति-रिवाजों में थीं।

115. (A) तर्कसंगत हैं, लेकिन अपनी सूचना और संज्ञानात्मक क्षमताओं की सीमा के भीतर।
हर्बर्ट साइमन की सीमित तर्कसंगतता का अर्थ है कि मनुष्य पूरी तरह तर्कहीन नहीं है, लेकिन वह असीमित बुद्धिमान भी नहीं है। किसी भी प्रशासनिक निर्णय को लेते समय प्रशासक के पास पूर्ण सूचना नहीं होती और समय भी सीमित होता है। इसलिए वह उन कुछ विकल्पों में से सबसे संतोषजनक विकल्प चुन लेता है जो उसे उस समय सही लगते हैं। यह विचार आर्थिक मानव की पूर्ण तर्कसंगतता के भ्रम को तोड़ता है और निर्णय लेने की प्रक्रिया को मानवीय सीमाओं के वास्तविक संदर्भ में प्रस्तुत करता है।

116. (B) शासन पर अनौपचारिक संगठन का प्रभाव।
किचन कैबिनेट जैसे समूहों का होना यह दर्शाता है कि औपचारिक संरचनाओं के बावजूद, शीर्ष नेतृत्व अक्सर व्यक्तिगत विश्वास और अनौपचारिक संबंधों के आधार पर सलाह लेना पसंद करता है। ये समूह आधिकारिक तौर पर घोषित नहीं होते, लेकिन इनके पास वास्तविक निर्णय लेने की बड़ी शक्ति होती है। यह अनौपचारिक संगठन की उस ताकत को उजागर करता है जो औपचारिक नियमों को दरकिनार कर सकती है। यह व्यवस्था प्रायः गोपनीयता के लिए अपनाई जाती है, लेकिन यह शासन में जवाबदेही और पारदर्शिता को प्रभावित कर सकती है।

117. (B) औपचारिक संरचना, अधिकार की रेखाएं और रिपोर्टिंग संबंध।
एक संगठनात्मक चार्ट संगठन के आंतरिक ढांचे का एक विहंगम दृश्य प्रस्तुत करता है। यह स्पष्ट करता है कि कौन सा पद किसके अधीन है, अधिकार ऊपर से नीचे कैसे प्रवाहित होते हैं और कर्मचारी अपनी रिपोर्ट किसे सौंपते हैं। यह चार्ट पदसोपान के सिद्धांत को दृश्य रूप में दर्शाता है। इसके माध्यम से किसी भी नए कर्मचारी को संगठन के औपचारिक कार्यों और कमान की श्रृंखला को समझने में आसानी होती है। यह संगठन में अनुशासन, स्पष्टता और व्यवस्थित कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण साधन है।

118. (A) व्यवस्था
हेनरी फेयोल द्वारा प्रतिपादित व्यवस्था का सिद्धांत संगठन में भौतिक और सामाजिक सुव्यवस्था पर बल देता है। इसका अर्थ है कि संगठन के पास प्रत्येक वस्तु और प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक निश्चित स्थान होना चाहिए। जब संसाधन और कर्मचारी अपने सही स्थान पर होते हैं, तो समय की बर्बादी कम होती है और कार्यकुशलता बढ़ती है। यह सिद्धांत केवल सफाई तक सीमित नहीं है, बल्कि यह संसाधनों के तार्किक आवंटन और सही व्यक्ति को सही पद पर नियुक्त करने के बारे में है, जो संगठन की सफलता के लिए अनिवार्य है।

119. (B) लोकतांत्रिक मूल्यों और भागीदारी के साथ तीव्र विकास को संतुलित करना।
विकास प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह तेजी से आर्थिक प्रगति भी करना चाहता है और साथ ही यह भी सुनिश्चित करना चाहता है कि निर्णय प्रक्रिया में जनता की भागीदारी हो। कभी-कभी तीव्र विकास के लिए लिए गए सख्त निर्णय लोकतांत्रिक भावनाओं के विपरीत हो सकते हैं। इसलिए, विकासशील देशों के प्रशासकों को एक ऐसे मार्ग का चयन करना पड़ता है जहाँ वे दक्षता और समावेशन के बीच संतुलन बना सकें। यह संतुलन ही एक स्थायी और न्यायसंगत राष्ट्र के निर्माण के लिए आवश्यक माना जाता है।

120. (D) लोकतांत्रिक प्राधिकार
मैक्स वेबर ने प्राधिकार के तीन प्रमुख प्रकार बताए थे: पारंपरिक, करिश्माई और कानूनी-तर्कसंगत। पारंपरिक प्राधिकार रीति-रिवाजों पर आधारित होता है, करिश्माई प्राधिकार नेता के व्यक्तित्व पर, और कानूनी-तर्कसंगत प्राधिकार लिखित नियमों और पदों पर आधारित होता है। वेबर के वर्गीकरण में लोकतांत्रिक प्राधिकार एक अलग श्रेणी के रूप में नहीं है, क्योंकि वे मुख्य रूप से इस बात पर केंद्रित थे कि शासन को वैधता कैसे मिलती है। आधुनिक नौकरशाही कानूनी-तर्कसंगत प्राधिकार का सबसे सटीक और परिष्कृत उदाहरण मानी जाती है।

121. (B) अन्य विभागों को सामान्य हाउसकीपिंग और संस्थागत सेवाएं प्रदान करना।
सहायक एजेंसियाँ, जिन्हें हाउसकीपिंग एजेंसियाँ भी कहा जाता है, सीधे जनता की सेवा नहीं करतीं। उनका मुख्य कार्य अन्य सरकारी विभागों को वे सेवाएँ प्रदान करना है जो उनके दैनिक संचालन के लिए आवश्यक हैं, जैसे कि स्टेशनरी की आपूर्ति, छपाई, भवनों का रखरखाव या लेखा-जोखा रखना। ये एजेंसियाँ लाइन विभागों के कार्यों को सरल बनाती हैं ताकि वे अपने मुख्य लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकें। इनका अस्तित्व सरकार के भीतर आंतरिक दक्षता और विशेषज्ञता बढ़ाने के उद्देश्य से होता है।

NODIA

उसे बहुत अधिक लोगों को नियंत्रित करना पड़े, तो कार्य में ढिलाई और संचार में त्रुटि हो सकती है। सही क्षेत्र का निर्धारण कार्य की जटिलता और प्रबंधकों के कौशल पर निर्भर करता है। यह संगठन की संरचना को सपाट या लंबवत बनाने में मुख्य भूमिका निभाता है।

196. (B) सामाजिक अंतःक्रिया और अपनेपन की भावना
अनौपचारिक संगठन का उदय इसलिए होता है क्योंकि मनुष्य कार्यस्थल पर केवल मशीन की तरह काम नहीं करना चाहता, बल्कि उसे भावनात्मक सहयोग और सामाजिक पहचान की भी आवश्यकता होती है। जब कर्मचारी खाली समय में आपस में बात करते हैं और दोस्त बनाते हैं, तो वे एक अनौपचारिक नेटवर्क का निर्माण करते हैं। यह नेटवर्क उन्हें सुरक्षा, अपनेपन और तनाव से मुक्ति का अहसास कराता है। यह सामाजिक जुड़ाव कार्यस्थल पर संतुष्टि बढ़ाता है और काम के बोझ को मानसिक रूप से हल्का करने में भूमिका निभाता है।

197. (C) निर्णय लेने की प्रक्रिया को कार्य स्थल के समीप लाता है।
विकेंद्रीकरण का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह निर्णय लेने की शक्ति को उन लोगों तक पहुँचाता है जो वास्तविक समस्याओं के सबसे निकट हैं। जब स्थानीय अधिकारियों को अधिकार दिए जाते हैं, तो वे अपनी विशिष्ट परिस्थितियों के अनुसार तुरंत प्रभावी कदम उठा सकते हैं। इससे आदेशों की प्रतीक्षा करने में होने वाला समय बचता है। यह न केवल प्रशासन को अधिक उत्तरदायी बनाता है, बल्कि नागरिकों के लिए सेवाओं की पहुँच को भी सरल और तीव्र बनाता है, जिससे शासन की विश्वसनीयता बढ़ती है।

198. (B) सार्वजनिक स्वामित्व, उत्तरदायित्व और व्यावसायिक प्रबंधन सिद्धांतों का मिश्रण।
लोक निगम एक ऐसा हाइब्रिड मॉडल है जो सरकार के सार्वजनिक सेवा के लक्ष्यों और निजी क्षेत्र की कार्यकुशलता को एक साथ लाता है। यह सरकार के स्वामित्व में तो होता है और संसद के प्रति जवाबदेह भी रहता है, लेकिन इसके दैनिक कार्यों में कोई राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होता। इसे अपने निर्णय लेने और धन जुटाने के लिए पूर्ण व्यावसायिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है। यह संतुलन सुनिश्चित करता है कि जनता को सेवाएँ भी मिलें और सरकारी खजाने पर कोई अतिरिक्त आर्थिक बोझ न पड़े, जो राष्ट्रहित में है।

199. (A) विधायी कार्य
राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक पर वीटो करना उनकी विधायी शक्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। चूँकि कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर न हों, वीटो के माध्यम से वे विधायिका द्वारा पारित किसी भी अनुचित कानून को रोक सकते हैं। यह कार्यपालिका को विधायी प्रक्रिया में एक नियंत्रक की भूमिका प्रदान करता है। यह सुनिश्चित करता है कि सरकार के विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों का संतुलन बना रहे और कोई भी अंग निरंकुश होकर कानून न बना सके।

200. (B) लालफीताशाही और कठोरता जैसे नकारात्मक प्रभाव।
ब्यूरो-पैथोलॉजी उन प्रशासनिक बुराइयों को संदर्भित करता है जो किसी भी नौकरशाही में समय के साथ पनप सकते हैं। इनमें नियमों का अत्यधिक पालन, कार्यों में अनावश्यक विलंब और जनता की समस्याओं के प्रति संवेदनहीनता सम्मिलित हैं। ये विकृतियाँ संगठन की दक्षता को नष्ट कर देती हैं और उसे जनविरोधी बना देती हैं। आधुनिक प्रशासनिक सुधारों का मुख्य उद्देश्य इन्हीं नौकरशाही विकारों को दूर करना है ताकि प्रशासन को अधिक पारदर्शी और नागरिक-हितैषी बनाया जा सके, जिससे लोकतंत्र मजबूत हो और जनता को लाभ मिले।

201. (B) वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत
फ्रेडरिक टेलर द्वारा प्रतिपादित वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत का यह दृढ़ विश्वास था कि प्रत्येक कार्य को करने का एक ही सर्वोत्तम तरीका होता है। इसके लिए उन्होंने समय और गति का विश्लेषण किया ताकि मानवीय प्रयासों की बर्बादी को रोका जा सके। टेलर का मानना था कि वैज्ञानिक अध्ययन के माध्यम से कार्य की दक्षता को अधिकतम किया जा सकता है। इस सिद्धांत ने कार्य के मानकीकरण और श्रमिकों के विशेष प्रशिक्षण पर बल दिया, जिससे औद्योगिक युग में उत्पादन की गति में क्रांतिकारी परिवर्तन आया।

202. (B) पारिस्थितिकीय
फ्रेड रिग्स का पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण इस विचार पर आधारित है कि एक प्रशासनिक प्रणाली अपने आसपास के सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण की उपज होती है। रिग्स ने संग्लन और विवर्तित समाजों के बीच की संक्रमणकालीन अवस्था को प्रिज्मीय समाज कहा। यह मॉडल बताता है कि कैसे विकासशील देशों में आधुनिक नियम और पुरानी प्रथाएँ एक साथ मौजूद रहकर प्रशासन को प्रभावित करती हैं। यह दृष्टिकोण लोक प्रशासन को समझने के लिए केवल आंतरिक संरचना के बजाय व्यापक परिवेश के अध्ययन पर विशेष बल देता है।

203. (B) सामाजिक परिवर्तन के लिए योजना बनाना और उसका प्रबंधन करना।
विकास प्रशासन का मुख्य उद्देश्य समाज में सकारात्मक बदलाव लाना और नागरिकों के कल्याण के लिए ठोस कार्य करना है। यह प्रशासन की पुरानी और स्थिर परंपराओं से हटकर नवाचार और लक्ष्यों की प्राप्ति पर ध्यान केंद्रित करता है। यह केवल नियमों के पालन तक सीमित नहीं है, बल्कि राष्ट्र निर्माण और आर्थिक विकास की परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए समर्पित है। यह दृष्टिकोण लोक प्रशासन को अधिक प्रगतिशील और परिणाम-आधारित बनाकर विकासशील देशों की विशिष्ट समस्याओं का प्रभावी समाधान प्रस्तुत करता है।

204. (A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
पदसोपान किसी भी बड़े संगठन की आधारशिला है क्योंकि यह ऊपर से नीचे तक अधिकार की एक स्पष्ट रेखा स्थापित करता है। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक कर्मचारी को पता हो कि उसे किसके प्रति जवाबदेह होना है। इसके माध्यम से वरिष्ठ अधिकारी अपने कार्यों को अधीनस्थों को सौंप

Click Here to Buy book on Amazon

276. (B) यह मान लेना कि एक संदर्भ में कार्य करने वाली प्रथा दूसरे संदर्भ में भी कार्य करेगी।
तुलनात्मक लोक प्रशासन में पारिस्थितिकीय भ्रम तब होता है जब एक विद्वान यह मान लेता है कि जो प्रशासनिक तकनीकें किसी एक देश में सफल रही हैं, वे किसी दूसरे देश में भी वही परिणाम देंगी। यह भ्रम स्थानीय सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के प्रभाव की उपेक्षा करता है। फ्रेड रिग्स ने इसके विरुद्ध चेतावनी दी थी क्योंकि प्रशासन अपने परिवेश का हिस्सा होता है। सफल प्रशासन के लिए यह आवश्यक है कि नीतियों को वहां के विशिष्ट सामाजिक ढांचे और मूल्यों के अनुसार ढाला जाए, तभी वांछित परिणाम प्राप्त होंगे।

277. (A) एक बहुल कार्यपालिका जो राजनीतिक और प्रशासनिक नेतृत्व को जोड़ती है।
संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिमंडल एक बहुल कार्यपालिका के रूप में कार्य करता है क्योंकि इसमें निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते हैं। मंत्रिमंडल के सदस्य न केवल राजनीतिक नेता होते हैं, बल्कि वे विभिन्न प्रशासनिक विभागों के प्रमुख भी होते हैं। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि नीतियों के निर्माण और उनके क्रियान्वयन के बीच एक मजबूत कड़ी बनी रहे। मंत्रिमंडल सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करता है, जहाँ सभी सदस्य सरकार की नीतियों के लिए संसद के प्रति जवाबदेह होते हैं, जो आधुनिक लोकतंत्र का मूल आधार है।

278. (C) कार्य नियमित हों और अधीनस्थ प्रशिक्षित हों।
नियंत्रण का एक विस्तृत क्षेत्र तब सबसे अधिक सफल होता है जब संगठन के कार्य सरल और नियमित हों। ऐसी स्थिति में, अधीनस्थ अनुभवी और प्रशिक्षित होते हैं, इसलिए उन्हें हर छोटे काम के लिए अपने वरिष्ठ के मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं होती। प्रबंधक एक ही समय में कई लोगों पर नजर रख सकता है क्योंकि जटिलताएं कम होती हैं। यह व्यवस्था संगठन में प्रबंधन के स्तरों को कम करती है, संचार को तेज करती है और कर्मचारियों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करती है, जिससे प्रशासनिक दक्षता में उल्लेखनीय वृद्धि और सकारात्मकता आती है।

279. (A) विभाग
सरकार के सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय, जैसे कि गृह और रक्षा, हमेशा विभाग के रूप में संगठित किए जाते हैं। विभाग सरकार की पारंपरिक और अनुशासित प्रशासनिक इकाई है। प्रत्येक विभाग सीधे एक कैबिनेट मंत्री के नियंत्रण में होता है, जो उसकी नीतियों के लिए संसद के प्रति जवाबदेह होता है। विभागों में पदसोपान की एक कड़ी व्यवस्था होती है जो ऊपर से नीचे तक स्पष्ट जवाबदेही सुनिश्चित करती है। यह ढाँचा सरकारी प्राथमिकताओं को व्यवस्थित रूप से लागू करने और सार्वजनिक निधि पर कड़ा नियंत्रण बनाए रखने के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है।

280. (C) सत्तावाद की ओर झुकाव।
विकास प्रशासन की एक प्रमुख आलोचना यह रही है कि तीव्र विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने की जल्दी में, यह अक्सर सत्तावाद की ओर झुक जाता है। इसमें सारा अधिकार और योजना निर्माण की शक्ति सरकार और नौकरशाही के हाथों में केंद्रित हो जाती है, जिससे स्थानीय समुदायों की वास्तविक भागीदारी कम हो सकती है। आलोचकों का मानना है कि यह दृष्टिकोण ऊपर से नीचे का हो जाता है, जहाँ प्रशासन खुद को समाज का भाग्य विधाता समझने लगता है और लोकतांत्रिक मूल्यों की अनजाने में अनदेखी हो सकती है, जो दोषपूर्ण है।

281. (C) आदेश देने का अधिकार
लाइन और स्टाफ के बीच का सबसे मूलभूत अंतर आदेश देने का अधिकार है। लाइन अधिकारियों के पास अपने अधीनस्थों को प्रत्यक्ष निर्देश देने और नीतियों को लागू करने का कार्यकारी अधिकार होता है, क्योंकि वे संगठन के मुख्य लक्ष्यों के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसके विपरीत, स्टाफ अधिकारी विशेषज्ञों के रूप में केवल परामर्श और अनुसंधान का कार्य करते हैं। उनके पास किसी को आदेश देने या कोई निर्णय थोपने की शक्ति नहीं होती। यह अंतर संगठन में कमान की अखंडता बनाए रखने और जवाबदेही को स्पष्ट करने के लिए अपरिहार्य माना जाता है।

282. (B) सोपानिक श्रृंखला (पदसोपान)
गैंगप्लैंक पदसोपान के उस कठोर नियम को तोड़ने का एक माध्यम है जो संचार को केवल कमान की श्रृंखला तक सीमित रखता है। पदसोपान में सूचनाओं के आदान-प्रदान में बहुत समय लगता है क्योंकि फाइल को कई स्तरों से गुजरना पड़ता है। गैंगप्लैंक के माध्यम से एक ही स्तर के कर्मचारी सीधे संवाद कर सकते हैं, जिससे संचार की गति बढ़ती है और त्वरित निर्णय लेना संभव होता है। हेनरी फेयोल ने आपातकालीन स्थितियों में समय की बर्बादी को रोकने के लिए इस लचीलेपन को संगठन के लिए अत्यंत आवश्यक और उपयोगी बताया था।

283. (D) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।
परिषद या बोर्ड जैसे सामूहिक निकाय त्वरित कार्यकारी कार्रवाई के लिए कभी भी प्रभावी नहीं होते, क्योंकि वहां हर निर्णय चर्चा के बाद लिया जाता है, जिसमें समय लगता है। हालांकि, कथन II बिल्कुल सही है क्योंकि परिषद का असली लाभ विचार-विमर्श में है। यह विभिन्न दृष्टिकोणों को सामने लाता है और किसी एक व्यक्ति की मनमानी को रोकता है। यह प्रणाली उन कार्यों के लिए सर्वोत्तम है जहाँ नीतियों की गंभीरता और निष्पक्षता, निर्णय लेने की गति से अधिक महत्वपूर्ण होती है, जैसे नियमन या उच्च-स्तरीय योजना निर्माण।

284. (C) मुख्य कार्यपालिका
प्रशासकीय राज्य के उदय का अर्थ है कि आधुनिक युग में सरकार के कार्य और प्रभाव क्षेत्र में अत्यधिक विस्तार हुआ है। इस प्रक्रिया ने मुख्य कार्यपालिका की शक्तियों और भूमिका को सबसे अधिक बढ़ाया है। अब मुख्य कार्यपालिका केवल शांति-व्यवस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि वह आर्थिक विकास और जन कल्याण के विशाल तंत्र का नेतृत्व करती है। सभी महत्वपूर्ण प्रशासनिक शक्तियाँ और निर्णय लेने के अधिकार इसी संस्था में केंद्रित हो गए हैं, जिससे वह शासन का सबसे शक्तिशाली केंद्र बन गई है, जो लोकतंत्र में एक नई चुनौती है।

NODIA

STUDYING FROM PDFs?

THINK AGAIN.

If you are studying only from PDFs,
you are wasting valuable time.

Research shows that learning from

PRINTED BOOKS has up to

4× HIGHER RETENTION

than studying from screens.

PRINT BOOK = BETTER MEMORY

PDF = LOWER RETENTION

Those who study from **PRINTED BOOKS**
move **AHEAD.**

Others are left **BEHIND**
in competition.

In competitive exams,
being average is not enough.

STAY ONE STEP AHEAD.

214. (C) स्वीकृति का क्षेत्र
चेस्टर बर्नार्ड द्वारा दी गई उदासीनता का क्षेत्र की अवधारणा को हर्बर्ट साइमन ने स्वीकृति का क्षेत्र के रूप में और अधिक स्पष्ट किया। यह वह मनोवैज्ञानिक सीमा है जिसके भीतर एक अधीनस्थ अपने वरिष्ठ के आदेशों को बिना किसी विरोध के स्वीकार कर लेता है। कर्मचारी इन आदेशों को अपनी सेवा शर्तों का एक स्वाभाविक हिस्सा मानता है। एक संगठन की स्थिरता इस बात पर निर्भर करती है कि यह क्षेत्र कितना विस्तृत है। यदि आदेश इस सीमा से बाहर होते हैं, तो कर्मचारी के भीतर असंतोष पैदा हो सकता है।

215. (B) तकनीकी विशेषज्ञों का उदय जो दिशा-निर्देश देते हैं।
आधुनिक शासन व्यवस्था में आदेश की एकता को बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो गया है क्योंकि अब केवल एक वरिष्ठ अधिकारी का आदेश पर्याप्त नहीं होता। जटिल कार्यों को पूरा करने के लिए कर्मचारियों को विभिन्न तकनीकी विशेषज्ञों, जैसे इंजीनियरों या आईटी विशेषज्ञों से भी निर्देश लेने पड़ते हैं। जब एक कर्मचारी को अपने प्रशासनिक अधिकारी के साथ इन विशेषज्ञों की बात भी माननी पड़ती है, तो दोहरे कमान की स्थिति पैदा हो जाती है। कार्यात्मक विशेषज्ञता का यह उदय पारंपरिक पदसोपान के नियमों को कमजोर करता है।

216. (C) वुड्रो विल्सन
वुड्रो विल्सन ने ही लोक प्रशासन के अध्ययन के दो मुख्य उद्देश्य बताए थे। पहला यह कि सरकार सफलतापूर्वक क्या कर सकती है और दूसरा यह कि वह इन कार्यों को अधिकतम दक्षता और न्यूनतम लागत के साथ कैसे कर सकती है। विल्सन का यह प्रश्न प्रशासन को राजनीति से अलग एक स्वतंत्र विज्ञान के रूप में स्थापित करने की दिशा में पहला महत्वपूर्ण कदम था। उन्होंने शासन की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने के लिए वैज्ञानिक और व्यावसायिक दृष्टिकोण अपनाने पर बल दिया था, जो क्रांतिकारी था।

217. (A) केवल 1 और 2
औपचारिक संगठन एक सचेत रूप से निर्मित ढाँचा है जिसे विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए तार्किक रूप से तैयार किया जाता है। इसकी संरचना, नियम और अधिकार लिखित रूप में होते हैं, जिन्हें प्रायः एक संगठनात्मक चार्ट द्वारा दर्शाया जाता है। कथन 3 गलत है क्योंकि सामाजिक संबंधों पर आधारित ढाँचा अनौपचारिक संगठन कहलाता है। औपचारिक संगठन में कार्य व्यक्तिगत पसंद के बजाय निर्धारित पदों और नियमों के अनुसार किए जाते हैं, जिससे संगठन में स्थिरता, अनुशासन और कार्य की निरंतरता बनी रहती है।

218. (B) इनपुट
व्यवस्था दृष्टिकोण के अनुसार, वातावरण वह विशाल स्रोत है जहाँ से कोई भी संगठन अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए आवश्यक संसाधन प्राप्त करता है। इन संसाधनों को इनपुट कहा जाता है, जिसमें कच्चा माल, पूँजी, मानवीय श्रम और सूचना सम्मिलित हैं। संगठन इन इनपुट्स को अपनी आंतरिक प्रक्रियाओं के माध्यम से संसाधित करता है और समाज के लिए उपयोगी परिणाम तैयार करता है। वातावरण और संगठन के बीच यह निरंतर चलने वाला विनिमय ही संगठन को जीवित रखता है और उसे बाहरी परिवर्तनों के अनुकूल बनाता है।

219. (A) एक राजनीतिक नियुक्त व्यक्ति या निर्वाचित अधिकारी
सरकारी विभाग का शीर्ष प्रमुख सामान्यतः एक राजनीतिक कार्यपालक होता है, जैसे कि एक मंत्री। यह व्यवस्था लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए की जाती है ताकि प्रशासन सीधे जनता के प्रति जवाबदेह हो। मंत्री नीतिगत दिशा-निर्देश तय करता है और विभाग की गतिविधियों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। दैनिक कार्यों को चलाने में उन्हें करियर सिविल सेवकों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। यह राजनीतिक नेतृत्व और प्रशासनिक विशेषज्ञता का एक सफल समन्वय है जो आधुनिक लोकतंत्र का आधार है।

220. (A) यह सुनिश्चित करना कि विधियों को ईमानदारी से कार्यान्वित किया जाए।
मुख्य कार्यपालिका की मुख्य प्रशासक के रूप में प्राथमिक जिम्मेदारी यह देखना है कि विधायिका द्वारा पारित कानूनों को प्रशासन द्वारा पूरी निष्ठा के साथ लागू किया जाए। इस भूमिका में वह सरकारी मशीनरी का समन्वय करती है, विभागों के कार्यों की देखरेख करती है और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करती है। वह प्रशासन में अनुशासन बनाए रखने और संसाधनों के सही आवंटन के लिए जवाबदेह होती है। इस प्रकार, वह यह सुनिश्चित करती है कि शासन व्यवस्था पारदर्शी और परिणाम-आधारित बनी रहे।

221. (B) सामाजिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण
हाथोर्न प्रयोगों से पहले प्रशासन को केवल एक यांत्रिक प्रक्रिया माना जाता था जहाँ आर्थिक प्रोत्साहन ही प्रेरणा का मुख्य स्रोत थे। एल्टन मेयो द्वारा किए गए इन प्रयोगों ने सिद्ध कर दिया कि कर्मचारी एक सामाजिक प्राणी है जिसकी कार्यक्षमता उसके आपसी संबंधों और मनोवैज्ञानिक संतुष्टि पर निर्भर करती है। इसने संगठनात्मक अध्ययन में मानवीय तत्व को सबसे ऊपर रखा। इसके बाद से, नेतृत्व की शैली और अनौपचारिक समूहों का अध्ययन लोक प्रशासन का एक अनिवार्य और अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है।

222. (B) निष्पादन में एकता, ऊर्जा और तत्परता
एकल मुख्य कार्यपालिका में शक्ति एक ही व्यक्ति में केंद्रित होने के कारण निर्णयों में अत्यधिक तीव्रता और स्पष्टता रहती है। जहाँ बहुल कार्यपालिका में आपसी चर्चा के कारण निर्णय लेने में देरी हो सकती है, वहीं एकल कार्यपालिका संकट के समय तुरंत निर्णायक कदम उठा सकती है। यह व्यवस्था नीतियों के कार्यान्वयन में निरंतरता और दृढ़ता प्रदान करती है। इसमें उत्तरदायित्व का कोई विभाजन नहीं होता, जिससे प्रशासन में ऊर्जा और कमान की एकता बनी रहती है, जो प्रभावी शासन के लिए अनिवार्य है।

223. (B) नौकरशाही
लालफीताशाही शब्द का प्रयोग नौकरशाही की उस नकारात्मक विशेषता को दर्शाने के लिए किया जाता है जहाँ नियमों और लंबी कागजी कार्रवाई को वास्तविक कार्य से अधिक महत्व

Downloaded from www.pdf.tube

अधिक सौहार्दपूर्ण बनता है और सामूहिक मनोबल में उल्लेखनीय वृद्धि होती है, जो हितकारी है।

259. (B) प्रशासनिक और राजनीतिक नियंत्रण
बजट तैयार करने की शक्ति मुख्य कार्यपालिका के लिए प्रशासन पर नियंत्रण रखने का सबसे बड़ा अस्त्र है। धन के आवंटन के माध्यम से वह यह तय करती है कि कौन सी नीतियों को प्राथमिकता मिलेगी और कौन से विभाग अधिक महत्वपूर्ण होंगे। यह प्रक्रिया कार्यपालिका को विभागों की दक्षता और उनके खर्चों की निगरानी करने का अवसर देती है। बजट केवल वित्तीय विवरण नहीं है, बल्कि यह सरकार की राजनीतिक प्राथमिकताओं और प्रशासनिक लक्ष्यों का एक सशक्त घोषणापत्र होता है जो पूरे शासन तंत्र को सही दिशा में निर्देशित करता है।

260. (B) मानव संबंध और व्यवहारवाद
यह विचार कि प्रशासन केवल फाइलों का ढेर नहीं है, बल्कि व्यक्तियों के माध्यम से कार्य करवाने की कला है, मानव संबंध और व्यवहारवादी विचारधाराओं का मूल केंद्र है। ये दृष्टिकोण मानते हैं कि संगठन की सफलता अंततः इस बात पर निर्भर करती है कि प्रबंधक अपने कर्मचारियों को कितना बेहतर समझते हैं और उन्हें काम के लिए कितना प्रेरित कर पाते हैं। इसमें नेतृत्व और मानवीय मनोविज्ञान को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। यह विचारधारा प्रशासन को यांत्रिक जकड़न से निकालकर उसे एक जीवंत मानवीय प्रक्रिया के रूप में स्थापित करती है।

261. (C) विवर्तित समाज
फ्रेड रिग्स ने संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे विकसित देशों को विवर्तित समाज की श्रेणी में रखा है। ऐसे समाजों की मुख्य विशेषता यह है कि वहाँ कार्यों का अत्यधिक विशेषीकरण होता है और प्रत्येक प्रशासनिक कार्य के लिए अलग और विशिष्ट संरचनाएं मौजूद होती हैं। यहाँ नियम स्पष्ट होते हैं, भर्ती योग्यता के आधार पर होती है और प्रशासन में उच्च स्तर की तार्किकता पाई जाती है। विवर्तित समाज प्रिज्मीय या संग्लन समाजों के लिए विकास और आधुनिकता का एक मानक मॉडल प्रस्तुत करता है, जिसे प्राप्त करना विकासशील देशों का लक्ष्य होता है।

262. (A) अधिकतम उत्तरदायित्व और नियंत्रण
संगठन के विभागीय रूप का सबसे बड़ा गुण यह है कि इसमें उत्तरदायित्व की रेखाएं बहुत स्पष्ट होती हैं। प्रत्येक विभाग एक मंत्री के अधीन होता है, जो सीधे विधायिका और जनता के प्रति जवाबदेह होता है। विभाग के भीतर पदसोपान का कड़ाई से पालन किया जाता है, जिससे वरिष्ठ अधिकारी अपने अधीनस्थों के कार्यों पर पूरा नियंत्रण रख सकते हैं। यह ढाँचा सुनिश्चित करता है कि सार्वजनिक निधि का उपयोग नियमों के अनुसार हो और सरकारी नीतियों का निष्ठापूर्वक पालन किया जाए। यह शासन में स्थिरता और कड़ी निगरानी के लिए उपयुक्त है।

263. (D) 1, 2 और 3
नौकरशाही के कुछ नकारात्मक पहलू उसके कामकाज में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। लालफीताशाही के कारण निर्णय लेने में अनावश्यक देरी होती है। लक्ष्य विस्थापन तब होता है जब कर्मचारी नियमों के पालन को ही अपना अंतिम लक्ष्य मान लेते हैं और वास्तविक जनहित को भूल जाते हैं। निर्वैयक्तिकता से प्रशासन जड़ और संवेदनहीन हो जाता है क्योंकि वह व्यक्तियों को केवल फाइलों की तरह देखता है। ये सभी विकृतियां नौकरशाही की दक्षता को कम करती हैं और उसे आम नागरिकों की जरूरतों से दूर ले जाती हैं, जिससे सुधार की आवश्यकता बढ़ती है।

264. (B) एक मैट्रिक्स या परियोजना-आधारित संरचना
आदेश की एकता का सिद्धांत मैट्रिक्स संरचना में विफल हो जाता है। मैट्रिक्स संगठन में कर्मचारी को एक ही समय में अपने स्थायी विभाग के प्रमुख और अपनी वर्तमान परियोजना के प्रबंधक, दोनों से निर्देश लेने पड़ते हैं। यह दोहरी कमान की स्थिति पैदा करता है। आधुनिक जटिल परियोजनाओं में, जहाँ विभिन्न क्षेत्रों की विशेषज्ञता एक साथ चाहिए होती है, वहां यह संरचना लचीलापन तो लाती है, लेकिन यह संगठन के पारंपरिक अनुशासन और एकल कमान के नियमों को चुनौती देती है। यह संरचना समन्वय के लिए उच्च स्तर की परिपक्वता मांगती है।

265. (A) परिवर्तन और सामाजिक-आर्थिक प्रगति पर इसका ध्यान।
पारंपरिक प्रशासन जहाँ केवल यथास्थिति बनाए रखने और शांति-व्यवस्था तक सीमित था, वहीं विकास प्रशासन का पूरा ध्यान समाज में सकारात्मक बदलाव लाने पर है। यह प्रशासन परिणाम-उन्मुख होता है और राष्ट्र निर्माण के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नवाचार के साथ कार्य करता है। यह विकासशील देशों की विशिष्ट समस्याओं को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसकी गतिशीलता और जन-केंद्रित दृष्टिकोण ही इसे पुरानी नौकरशाही के जड़ ढांचे से अलग और अधिक प्रभावी बनाता है, जिससे विकास की गति को बल मिलता है और लक्ष्य प्राप्त होते हैं।

266. (B) स्टाफ इकाई
किसी मंत्रालय से जुड़ा थिंक टैंक एक आदर्श स्टाफ इकाई के रूप में कार्य करता है। इसका मुख्य उत्तरदायित्व मंत्रालय को गहन शोध और नीतिगत सलाह प्रदान करना है। इसके पास कोई कार्यकारी शक्ति नहीं होती और न ही यह सीधे जनता के लिए सेवाओं का कार्यान्वयन करता है। यह केवल पर्दे के पीछे रहकर सरकार की बौद्धिक क्षमता और योजना निर्माण की शक्ति को बढ़ाने का कार्य करता है। स्टाफ इकाइयां विशेषज्ञों के माध्यम से लाइन अधिकारियों को अधिक सूचित और दूरगामी निर्णय लेने में सक्षम बनाती हैं, जो आधुनिक शासन में अनिवार्य है।

267. (A) राजनीति और प्रशासन आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं।
आधुनिक प्रशासनिक विद्वानों ने यह मान लिया है कि राजनीति और प्रशासन के बीच कोई सख्त दीवार खड़ी करना असंभव है। राजनीति-प्रशासन द्विभाजन का अंत इस समझ के साथ हुआ

NODIA

प्रशासनिक अधिकारियों की सलाह पर निर्भर रहते हैं। चूँकि प्रशासन और राजनीति के कार्य आपस में गहराई से गुंथे हुए हैं, इसलिए उन्हें पूरी तरह अलग करना व्यावहारिक नहीं है।

233. (A) श्रम विभाजन या विशेषीकरण
श्रम विभाजन का सिद्धांत कहता है कि किसी बड़े कार्य को एक ही व्यक्ति द्वारा किए जाने के बजाय उसे छोटे हिस्सों में बाँट दिया जाना चाहिए। जब एक कर्मचारी किसी एक ही कार्य को बार-बार करता है, तो वह उस क्षेत्र में विशेषज्ञ बन जाता है, जिससे उसकी कार्यक्षमता बढ़ जाती है। यह प्रक्रिया संगठन की कुल उत्पादकता को बढ़ाने में बहुत सहायक होती है। आधुनिक औद्योगिक क्रांति और बड़े पैमाने पर उत्पादन की नींव इसी विशेषीकरण के सिद्धांत पर टिकी हुई है, जिससे कार्य में सटीकता और गति आती है।

234. (B) एक ही स्तर पर कर्मचारियों के बीच तीव्र संचार की सुविधा प्रदान करना।
गैंगप्लैंक की अवधारणा हेनरी फेयोल ने पदसोपान के कठोर नियमों के विकल्प के रूप में दी थी। पदसोपान में संचार सदैव ऊपर से नीचे होता है, जिसमें बहुत समय लगता है। गैंगप्लैंक के माध्यम से एक ही स्तर के दो अलग-अलग विभागों के अधिकारी आपस में सीधे संवाद कर सकते हैं, बशर्ते उन्होंने अपने वरिष्ठों को इसकी जानकारी दे दी हो। यह तंत्र विशेष रूप से आपातकालीन स्थितियों में समय की बचत करने और कार्यों में समन्वय को तेज करने के लिए बनाया गया था ताकि दक्षता बनी रहे।

235. (C) आर्थिक मानव
हर्बर्ट साइमन ने सीमित तर्कसंगतता का विचार शास्त्रीय अर्थशास्त्र के आर्थिक मानव के विरोध में प्रस्तुत किया था। आर्थिक मानव वह काल्पनिक पात्र है जिसके पास सभी सूचनाएँ होती हैं और जो सदैव अपना लाभ अधिकतम करने के लिए निर्णय लेता है। साइमन ने तर्क दिया कि वास्तविक जीवन में मनुष्यों की बौद्धिक क्षमता और सूचनाएँ सीमित होती हैं। इसलिए वे इष्टतम विकल्प के बजाय संतोषजनक विकल्प चुनते हैं। इस प्रकार उन्होंने आर्थिक मानव के स्थान पर प्रशासनिक मानव की अधिक व्यवहारिक अवधारणा प्रस्तुत की।

236. (C) उनके पर्यवेक्षण के प्रति जागरूकता।
हाथोर्न प्रयोगों के दौरान यह एक महत्वपूर्ण खोज थी कि श्रमिकों के व्यवहार में परिवर्तन केवल इसलिए आया क्योंकि उन्हें पता था कि उन पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। इसे हाथोर्न प्रभाव कहा गया। यह दर्शाता है कि मानवीय व्यवहार केवल भौतिक वातावरण से ही नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक कारकों से भी प्रभावित होता है। जब कर्मचारियों को लगता है कि प्रबंधन उनकी परवाह कर रहा है और उन्हें विशेष महत्व दे रहा है, तो उनकी कार्यक्षमता और सहयोग करने की इच्छा में स्वतः ही उल्लेखनीय वृद्धि हो जाती है।

237. (C) विचार-विमर्श को बढ़ावा देना और शक्ति का प्रसार करना।
बहुल कार्यपालिका का मुख्य उद्देश्य किसी एक व्यक्ति को बहुत अधिक शक्तिशाली होने से रोकना और शासन को अधिक लोकतांत्रिक बनाना है। इसमें निर्णय लेने की शक्ति सदस्यों के एक समूह में विभाजित होती है, जिससे विभिन्न दृष्टिकोणों पर चर्चा करने का अवसर मिलता है। यह प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि महत्वपूर्ण निर्णय किसी एक व्यक्ति की सनक के बजाय सामूहिक बुद्धिमत्ता के बाद ही लिए जाएँ। यह व्यवस्था उन संस्थाओं के लिए उपयुक्त है जहाँ विविधता और निष्पक्षता को त्वरित निर्णय लेने से अधिक महत्व दिया जाता है।

238. (D) 1, 2 और 3
लोक प्रशासन के सिद्धांतों का विकास विभिन्न चरणों में हुआ है जो एक-दूसरे के पूरक हैं। शास्त्रीय सिद्धांत ने संगठन को कुशल बनाने के लिए औपचारिक संरचना पर बल दिया। मानव संबंध सिद्धांत ने सिद्ध किया कि उत्पादकता के लिए कर्मचारियों की सामाजिक और मनोवैज्ञानिक खुशी भी अनिवार्य है। व्यवस्था सिद्धांत ने इन विचारों को और आगे बढ़ाते हुए संगठन को एक खुली व्यवस्था माना जो अपने बाहरी वातावरण के साथ निरंतर लेन-देन करती है। ये तीनों दृष्टिकोण मिलकर ही आधुनिक संगठनात्मक व्यवहार की पूरी तस्वीर पेश करते हैं।

239. (C) विभाग
सरकारी सेवाओं को प्रदान करने के लिए विभाग को सबसे बुनियादी और पारंपरिक संगठनात्मक रूप माना जाता है। प्रत्येक विभाग किसी विशिष्ट कार्यक्षेत्र, जैसे कि कृषि या रक्षा, के लिए उत्तरदायी होता है। विभागों की संरचना पदसोपान पर आधारित होती है, जिससे जवाबदेही की एक स्पष्ट रेखा बनी रहती है। इनका सीधा नियंत्रण मंत्रियों के पास होता है, जो सार्वजनिक निधि के सही उपयोग और सरकारी नीतियों के सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करते हैं। यह शासन की निरंतरता बनाए रखने का सबसे विश्वसनीय माध्यम माना जाता है।

240. (B) प्रशासन और उसके सामाजिक परिवेश के बीच परस्पर संबंध।
फ्रेड रिग्स के अनुसार, लोक प्रशासन को समझने के लिए केवल कार्यालय के नियमों को पढ़ना पर्याप्त नहीं है। प्रशासन उस समाज का हिस्सा होता है जहाँ वह कार्य कर रहा है। पारिस्थितिकी का अर्थ है वे सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक शक्तियाँ जो प्रशासनिक व्यवहार को प्रभावित करती हैं और उससे प्रभावित भी होती हैं। जिस प्रकार एक पौधा अपनी जलवायु के अनुसार बढ़ता है, वैसे ही प्रशासन भी अपने परिवेश के अनुरूप ढलता है। यह दृष्टिकोण बताता है कि एक देश का प्रशासनिक मॉडल दूसरे में क्यों विफल हो सकता है।

241. (B) एक ही उद्देश्य वाली सभी गतिविधियों का एक प्रमुख और एक योजना होनी चाहिए।
हेनरी फेयोल द्वारा प्रतिपादित निर्देशन की एकता का सिद्धांत संगठन के प्रयासों में समन्वय और स्पष्टता लाने पर बल देता है। इसका अर्थ है कि समान लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए की जाने वाली सभी गतिविधियों का नेतृत्व एक ही व्यक्ति द्वारा किया

Click Here to Buy book on Amazon

जाना चाहिए और उनके पास एक ही मास्टर प्लान होना चाहिए। यह सिद्धांत संगठन को विभिन्न दिशाओं में भटकने से रोकता है और यह सुनिश्चित करता है कि सभी कर्मचारी एक ही लक्ष्य की ओर मिल-जुलकर आगे बढ़ें। यह अनुशासन और प्रभावी टीम वर्क की नींव रखता है।

242. (A) P-3, Q-4, R-1, S-2
मुख्य कार्यपालिका के विभिन्न स्वरूप दुनिया के अलग-अलग देशों में प्रचलित हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति एकल और शक्तिशाली कार्यपालिका का उदाहरण हैं। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री संसदीय प्रणाली में वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करते हैं। भारत के राष्ट्रपति राज्य के औपचारिक प्रमुख हैं। स्विट्जरलैंड की संघीय परिषद एक बहुल कार्यपालिका का उदाहरण है जहाँ शक्ति सात सदस्यों के बीच समान रूप से बँटी होती है। यह वर्गीकरण सत्ता के वितरण के अलग-अलग तरीकों को स्पष्ट करता है, जो वहां की राजनीतिक व्यवस्था के अनुकूल है।

243. (B) संगठनों के भीतर व्यक्तियों का वास्तविक व्यवहार।
व्यवहारवादी आंदोलन ने लोक प्रशासन के अध्ययन को केवल कानूनी नियमों से बाहर निकालकर मानवीय वास्तविकता से जोड़ा। इस दृष्टिकोण के समर्थकों का मानना था कि संगठन मशीनों के समूह नहीं हैं, बल्कि वे जीवित मनुष्यों की अंतःक्रियाओं का परिणाम हैं। उन्होंने यह अध्ययन किया कि कर्मचारी वास्तव में निर्णय कैसे लेते हैं और संचार उन्हें कैसे प्रभावित करता है। इस वैज्ञानिक विश्लेषण ने प्रशासन को अधिक यथार्थवादी बनाया, जिससे संगठनात्मक समस्याओं के गहरे समाधान मिलना संभव हुआ, जो केवल नियमों से संभव नहीं था।

244. (B) शासन की बढ़ती जटिलता।
आधुनिक युग में सरकार के कार्य बहुत ही जटिल और तकनीकी हो गए हैं। लाइन अधिकारियों के पास प्रशासन चलाने का अधिकार तो होता है, लेकिन उनके पास हर क्षेत्र जैसे कि कानून या आधुनिक तकनीक की विशेषज्ञता नहीं होती। इसी कमी को पूरा करने के लिए स्टाफ एजेंसियों का विकास हुआ। ये एजेंसियां विशेषज्ञों के माध्यम से अनुसंधान और योजना निर्माण का कार्य करती हैं ताकि मुख्य कार्यपालिका अधिक सूचित और प्रभावी निर्णय ले सके। यह विशेषज्ञता शासन की आधुनिक चुनौतियों का सामना करने के लिए अत्यंत अनिवार्य और महत्वपूर्ण है।

245. (C) महत्वपूर्ण निर्णय लेने का अधिकार पदसोपान के शीर्ष पर बना रहता है।
एक अत्यधिक केंद्रीकृत संगठन वह है जहाँ सत्ता और निर्णय लेने की शक्ति केवल शीर्ष अधिकारियों के हाथों में संकुचित रहती है। ऐसे संगठनों में निचले स्तर के प्रबंधकों को अपनी मर्जी से काम करने या कोई भी बदलाव करने की बहुत कम स्वतंत्रता होती है। उन्हें हर छोटे कार्य के लिए ऊपर से आदेशों की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। केंद्रीकरण नीतियों में कड़ी एकरूपता सुनिश्चित करता है, लेकिन इसके कारण निर्णय लेने की प्रक्रिया अक्सर बहुत धीमी हो जाती है और कर्मचारियों के मनोबल पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

246. (C) स्वतंत्र नियामक आयोग
स्वतंत्र नियामक आयोगों का गठन विशेष रूप से उन क्षेत्रों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है जहाँ निष्पक्षता की आवश्यकता होती है। इन आयोगों को सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण से दूर रखा जाता है ताकि उन पर तात्कालिक राजनीतिक दबाव न पड़े। इनके सदस्यों का कार्यकाल निश्चित होता है, जिससे वे बिना किसी डर के लंबे समय के हितों को ध्यान में रखकर निर्णय ले सकते हैं। यह संरचना तकनीकी और आर्थिक क्षेत्रों में जनता का विश्वास और बाजार में स्थिरता बनाए रखने के लिए अनिवार्य है, जिससे शासन में पारदर्शिता बढ़ती है।

247. (B) पदसोपानिक पदोन्नति प्रणाली
पीटर सिद्धांत एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक अवलोकन है, जो यह कहता है कि पदसोपान वाले किसी भी संगठन में प्रत्येक कर्मचारी अपनी अक्षमता के स्तर तक पदोन्नत होता रहता है। इसका अर्थ है कि एक व्यक्ति जो अपने वर्तमान पद पर अच्छा काम कर रहा है, उसे तब तक पदोन्नत किया जाता है जब तक वह एक ऐसे पद पर नहीं पहुँच जाता जिसके लिए वह योग्य नहीं है। यह सिद्धांत पदसोपानिक पदोन्नति की कमियों को उजागर करता है, जहाँ पिछली सफलता को भविष्य की योग्यता का एकमात्र पैमाना मान लिया जाता है, जो दोषपूर्ण है।

248. (B) एक व्यवस्था विभिन्न प्रारंभिक स्थितियों से एक ही अंतिम स्थिति तक पहुँच सकती है।
व्यवस्था दृष्टिकोण में एकसमानता का सिद्धांत बताता है कि खुली व्यवस्थाओं में एक ही लक्ष्य को प्राप्त करने के कई अलग-अलग रास्ते हो सकते हैं। एक संगठन अलग-अलग संसाधनों या रणनीतियों के बावजूद भी सफलता के एक ही मुकाम तक पहुँच सकता है। यह विचार प्रबंधकों को लचीला होने की प्रेरणा देता है। यह स्पष्ट करता है कि प्रबंधन का कोई एक ही सर्वोत्तम तरीका नहीं है, बल्कि परिस्थितियों के अनुसार अलग-अलग माध्यमों से भी वही उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं, जो संगठन की जीवंतता को दर्शाते हैं।

NODIA

249. (C) सरकारी तंत्र का प्रबंधन और देखरेख
मुख्य कार्यपालिका की प्रशासनिक भूमिका का मुख्य केंद्र बिंदु पूरे सरकारी तंत्र का कुशल संचालन है। इसमें वह विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करती है, प्रमुख पदों पर नियुक्तियाँ करती है और यह सुनिश्चित करती है कि सभी एजेंसियां नियमों के अनुसार कार्य करें। वह प्रशासन में अनुशासन बनाए रखने के लिए समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी करती है। यह भूमिका यह सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि सरकार द्वारा जनता के लिए बनाई गई नीतियां केवल फाइलों तक सीमित न रहें, बल्कि वे प्रभावी ढंग से लागू हों।

250. (B) राष्ट्रीय विकास को प्रोत्साहित करने और मार्गदर्शन करने के लिए।
विकास प्रशासन का मूल मंत्र यह है कि प्रशासन को केवल निष्क्रिय तरीके से नियम लागू नहीं करने चाहिए, बल्कि उसे समाज के उत्थान के लिए एक सक्रिय उपकरण के रूप में कार्य करना चाहिए। यह दृष्टिकोण राष्ट्रों को गरीबी और पिछड़ेपन से बाहर निकालने के लिए योजनाओं के कुशल क्रियान्वयन पर बल देता है। इसमें प्रशासक की भूमिका एक परिवर्तन एजेंट की होती है जो राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नवाचार और जन-भागीदारी को बढ़ावा देता है। यह प्रगतिशील राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है जो सतत विकास सुनिश्चित करती है।

251. (C) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
औपचारिक संगठन लिखित नियमों द्वारा परिभाषित होता है, जबकि अनौपचारिक संगठन मानवीय संबंधों से जन्म लेता है। कथन II गलत है क्योंकि एक प्रभावी प्रबंधक कभी भी अनौपचारिक संगठन की उपेक्षा नहीं करता। इसके विपरीत, वह इसे समझने का प्रयास करता है क्योंकि यह कर्मचारियों के मनोबल और सूचनाओं के प्रवाह को गहराई से प्रभावित करता है। जो प्रबंधक अनौपचारिक समूहों के साथ तालमेल बिठाते हैं, वे अक्सर अपने लक्ष्यों को अधिक सहजता और कर्मचारी सहयोग के साथ प्राप्त करने में सफल होते हैं, जो संगठन हित में है।

252. (C) समन्वय
जेम्स डी. मूनी ने समन्वय को संगठन का पहला और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत माना था। उनके अनुसार, सोपानिक प्रक्रिया के माध्यम से अधिकार का वितरण होता है जो समन्वय का आधार बनता है। कार्यात्मक प्रक्रिया का अर्थ है कार्यों का विशेषीकरण करना ताकि सभी इकाइयां अपने कार्यों को कुशलतापूर्वक करें। जब ये दोनों प्रक्रियाएँ मिल जाती हैं, तो संगठन के विभिन्न भागों के बीच समन्वय स्थापित होता है। समन्वय ही वह तत्व है जो संगठन की बिखरी हुई गतिविधियों को एक साझा लक्ष्य की दिशा में एकीकृत और प्रभावी बनाता है।

253. (C) निर्णय-निर्माण दृष्टिकोण
निर्णय-निर्माण दृष्टिकोण प्रशासन के अध्ययन का वह केंद्र बिंदु है जो यह मानता है कि प्रशासन वास्तव में निर्णय लेने का ही दूसरा नाम है। यह दृष्टिकोण केवल बाहरी संरचना को नहीं देखता, बल्कि यह समझने की कोशिश करता है कि एक प्रशासक के मन में क्या चलता है जब वह किसी विकल्प को चुनता है। इसमें प्रशासक के व्यक्तिगत मूल्यों और उसकी जानकारी के स्रोतों का गहन विश्लेषण किया जाता है। हर्बर्ट साइमन ने इस दृष्टिकोण के माध्यम से यह समझाया कि निर्णय ही प्रशासनिक कार्यों की वास्तविक चालक शक्ति और आधार हैं।

254. (A) वेबर की योग्यता-आधारित नौकरशाही
स्पॉइल्स सिस्टम या लूट प्रणाली वह व्यवस्था है जिसमें सरकारी पदों को योग्यता के बजाय राजनीतिक वफादारी के आधार पर पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। यह मैक्स वेबर के नौकरशाही सिद्धांत के बिल्कुल विपरीत है, जो यह कहता है कि नियुक्तियां केवल निष्पक्ष परीक्षा और योग्यता के आधार पर ही होनी चाहिए। वेबर का मानना था कि प्रशासन में दक्षता तभी आ सकती है जब उसे राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त रखा जाए। योग्यता-आधारित व्यवस्था ही एक पारदर्शी और सक्षम शासन सुनिश्चित करती है, जो लोकतंत्र के लिए अनिवार्य है।

255. (B) मुख्य कार्यपालिका की सहायता करने वाली एक स्टाफ एजेंसी।
प्रधानमंत्री कार्यालय एक अत्यंत शक्तिशाली स्टाफ एजेंसी है जिसका मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री को उनके व्यापक प्रशासनिक उत्तरदायित्वों को निभाने में सहायता प्रदान करना है। यह कार्यालय नीतिगत मुद्दों पर विशेषज्ञ सलाह देता है, विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित करता है और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों की निगरानी करता है। इसके पास स्वयं कोई लाइन अधिकार नहीं होता, लेकिन प्रधानमंत्री के साथ निकटता के कारण इसका प्रभाव बहुत अधिक होता है। यह शासन के सुचारू संचालन के लिए एक रणनीतिक केंद्र के रूप में कार्य करता है।

256. (B) व्यावसायिक स्वायत्तता और सार्वजनिक उत्तरदायित्व
लोक निगमों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि वे एक तरफ तो निजी कंपनियों की तरह स्वतंत्र रूप से अपने व्यावसायिक निर्णय लेना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन्हें सार्वजनिक उत्तरदायित्व का भी ध्यान रखना होता है। अत्यधिक स्वायत्तता जवाबदेही को कम कर सकती है, जबकि अत्यधिक सरकारी हस्तक्षेप उनकी व्यावसायिक कुशलता को नष्ट कर सकता है। इसलिए, एक सफल लोक निगम वही है जो इन दोनों विरोधाभासी लक्ष्यों के बीच एक कुशल और टिकाऊ संतुलन बनाए रखने में सक्षम हो, जिससे जनहित और लाभ दोनों सुनिश्चित हों।

257. (B) एक लंबवत संरचना
जब किसी संगठन में नियंत्रण का क्षेत्र संकीर्ण होता है, तो इसका अर्थ है कि एक प्रबंधक बहुत कम संख्या में अधीनस्थों का पर्यवेक्षण करता है। इस स्थिति में संगठन में ऊपर से नीचे तक कई पदसोपानिक स्तर बनाने पड़ते हैं, जिससे संगठन की आकृति लंबवत हो जाती है। ऐसी संरचना में नियंत्रण बहुत कड़ा होता है, जो अनुशासन के लिए अच्छा है। हालाँकि, इसकी मुख्य कमी यह है कि संचार को इतने सारे स्तरों से गुजरने में बहुत समय लगता है, जिससे निर्णय प्रक्रिया अत्यंत धीमी हो जाती है, जो आधुनिक समय में बाधक है।

258. (A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
चतुर प्रबंधक जानते हैं कि अनौपचारिक संगठन और उसकी ग्रेपवाइन संचार का एक अत्यंत शक्तिशाली माध्यम है। वे अक्सर इस चैनल का उपयोग महत्वपूर्ण सूचनाओं को अनौपचारिक रूप से फैलाने के लिए करते हैं ताकि कर्मचारियों की प्रतिक्रिया को पहले ही समझा जा सके। यह तरीका कर्मचारियों के बीच भ्रम को दूर करने और उनमें विश्वास जगाने में मदद कर सकता है। जब प्रबंधन अनौपचारिक नेटवर्क का सकारात्मक उपयोग करता है, तो कार्यस्थल का वातावरण

NODIA

सकते हैं, जिससे कार्यक्षमता बढ़ती है। यह ढाँचा संगठन में अनुशासन बनाए रखने और आदेशों के व्यवस्थित प्रवाह के लिए अपरिहार्य माना जाता है, जिससे पूरी प्रशासनिक मशीनरी तालमेल के साथ कार्य करती है।

205. (A) यह अफवाहें और त्रुटिपूर्ण सूचना प्रसारित कर सकता है।
अनौपचारिक संगठन और उसका मुख्य संचार माध्यम ग्रेपवाइन कभी-कभी संगठन के लिए गंभीर समस्या बन सकते हैं। चूँकि इसमें सूचना का कोई आधिकारिक स्रोत नहीं होता, इसलिए अक्सर आधी-अधूरी बातें या गलत अफवाहें बहुत तेजी से फैल जाती हैं। इससे कर्मचारियों में अनावश्यक डर और भ्रम पैदा हो सकता है, जो उनके मनोबल और उत्पादकता पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। यदि प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच पारदर्शिता की कमी हो, तो ग्रेपवाइन की ये बुराइयां संगठनात्मक शांति को भंग कर सकती हैं।

206. (B) विकेंद्रीकरण
प्रत्यायोजन वह प्रक्रिया है जिसमें एक वरिष्ठ अधिकारी अपने कुछ अधिकार और कार्य अपने अधीनस्थों को सौंपता है। यह विकेंद्रीकरण की दिशा में पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। इसके माध्यम से निर्णय लेने की शक्ति पदसोपान के निचले स्तरों तक पहुँचती है, जिससे कार्य में तेजी आती है और स्थानीय समस्याओं का समाधान संभव होता है। प्रत्यायोजन न केवल वरिष्ठों के कार्यभार को हल्का करता है, बल्कि यह कनिष्ठ अधिकारियों के भीतर जिम्मेदारी लेने और नेतृत्व करने के कौशल को भी विकसित करता है।

207. (C) परिषद
लोक निगम के लिए निदेशक मंडल एक परिषद के रूप में कार्य करता है। यह एक सामूहिक निकाय है जहाँ किसी एक व्यक्ति के निर्णय के बजाय आपसी सहमति और चर्चा को प्राथमिकता दी जाती है। मंडल का मुख्य कार्य संगठन की दीर्घकालिक नीतियां बनाना और प्रबंधन की देखरेख करना है। यह सामूहिक नेतृत्व सुनिश्चित करता है कि संगठन के निर्णय संतुलित हों और उसमें विभिन्न विशेषज्ञों के दृष्टिकोण शामिल हों। यह व्यक्तिगत निरंकुशता को रोकने और व्यावसायिक निष्पक्षता बनाए रखने का एक सशक्त माध्यम है।

208. (A) प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल
संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल में निहित होती है। यद्यपि सभी सरकारी कार्य औपचारिक रूप से राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं, लेकिन नीतियों का निर्धारण और वास्तविक निर्णय प्रधानमंत्री द्वारा ही लिए जाते हैं। मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, जो लोकतंत्र की एक प्रमुख विशेषता है। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि कार्यकारी शक्तियाँ उन लोगों के पास रहें जिन्हें जनता का विश्वास प्राप्त है और जो जनहित के लिए जवाबदेह हैं।

209. (B) सूचना प्रदान करने वाला एक खुफिया विश्लेषक।
सेना में स्टाफ कार्यों का मुख्य उद्देश्य कमांडर को निर्णय लेने के लिए आवश्यक सूचनाएं और तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करना है। एक खुफिया विश्लेषक स्वयं युद्ध नहीं लड़ता, बल्कि वह दुश्मन की गतिविधियों का विश्लेषण करके रणनीतिक जानकारी उपलब्ध कराता है। यह सूचना लाइन अधिकारियों को बेहतर और सटीक कार्रवाई करने में मदद करती है। स्टाफ एजेंसियां पर्दे के पीछे रहकर काम करती हैं और संगठन की बौद्धिक क्षमता और योजना निर्माण की शक्ति को कई गुना बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

210. (A) P-4, Q-2, R-1, S-3
संगठन के विभिन्न सिद्धांत प्रशासनिक ढांचे को व्यवस्थित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। सोपानिक सिद्धांत अधिकार की अटूट श्रृंखला को दर्शाता है। आदेश की एकता यह सुनिश्चित करती है कि एक अधीनस्थ को केवल एक ही अधिकारी से निर्देश मिलें। नियंत्रण का क्षेत्र एक अधिकारी के अधीन काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या को सीमित करता है। सहयोग की भावना का अर्थ है टीम के भीतर एकता और उत्साह। ये सभी तत्व मिलकर एक अनुशासित, समन्वित और प्रभावी संगठनात्मक वातावरण का निर्माण करते हैं।

211. (B) सामाजिक समता और प्रासंगिक
नवीन लोक प्रशासन आंदोलन 1960 के दशक के उत्तरार्ध में उभरा, जब विद्वानों ने महसूस किया कि पारंपरिक प्रशासन केवल दक्षता पर ध्यान दे रहा है, जबकि समाज की वास्तविक समस्याओं की उपेक्षा हो रही है। इस आंदोलन ने तर्क दिया कि प्रशासन को मूल्यों के प्रति तटस्थ नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे सामाजिक समता लाने के लिए सक्रिय रूप से कार्य करना चाहिए। इसका मुख्य जोर प्रशासन को समाज के लिए अधिक प्रासंगिक, जन-उन्मुख और परिवर्तनकारी बनाने पर था ताकि वंचित वर्गों को न्याय मिले।

212. (C) वे विरोधाभासी थे और उनमें वैज्ञानिक आधार का अभाव था।
हर्बर्ट साइमन ने शास्त्रीय सिद्धांतों की आलोचना इसलिए की क्योंकि वे अक्सर एक-दूसरे के उलट बात करते थे। उदाहरण के लिए, एक सिद्धांत विशेषज्ञता बढ़ाने के लिए कार्यों को बाँटने को कहता है, तो दूसरा नियंत्रण बढ़ाने के लिए स्तर कम करने को। साइमन ने इन्हें कहावतें कहा क्योंकि ये सुनने में अच्छी लगती हैं लेकिन वैज्ञानिक रूप से पूरी तरह सही नहीं होतीं। उनके अनुसार, इन सिद्धांतों में ठोस शोध की कमी थी। उन्होंने प्रशासन के अध्ययन में मानव व्यवहार के वैज्ञानिक विश्लेषण पर अधिक बल दिया।

213. (B) अधिक व्यावसायिक दक्षता और लचीलापन।
लोक निगम बनाने का प्राथमिक उद्देश्य यह है कि सरकारी सेवाओं को नौकरशाही की कठोरता और लालफीताशाही से मुक्त किया जा सके। निगमों को अपने स्वयं के वित्तीय संसाधन जुटाने और स्वतंत्र निर्णय लेने की स्वायत्तता दी जाती है। यह लचीलापन उन्हें निजी कंपनियों की तरह प्रतिस्पर्धी माहौल में कुशलतापूर्वक कार्य करने में सक्षम बनाता है। चूँकि उन्हें अपने खर्चे खुद उठाने पड़ते हैं, इसलिए उनमें लाभ कमाने और संसाधनों के कुशल उपयोग की भावना अधिक होती है, जो जनहित को सुनिश्चित करती है।

Downloaded from www.pdf.tube

कि प्रशासक केवल आदेशों को लागू करने वाली मशीनें नहीं हैं, बल्कि वे अपनी विशेषज्ञता के कारण नीति निर्धारण में भी सक्रिय भाग लेते हैं। मंत्री अक्सर जटिल निर्णयों के लिए अपने सचिवों की सलाह पर निर्भर रहते हैं। चूँकि नीतियां बनाना और उन्हें लागू करना एक ही प्रक्रिया के दो अविभाज्य हिस्से हैं, इसलिए प्रशासन को राजनीति के व्यापक संदर्भ में समझना ही यथार्थवादी है।

268. (C) व्यवस्था सिद्धांत
व्यवस्था सिद्धांत संगठन को एक सीखने वाली प्रणाली के रूप में देखता है। यह मानता है कि संगठन अपने बाहरी वातावरण के साथ निरंतर अंतःक्रिया करता है और वहां से प्राप्त प्रतिपुष्टि के आधार पर अपनी गलतियों को सुधारता है। प्रतिपुष्टि एक मार्गदर्शक की तरह कार्य करती है जो संगठन को यह बताती है कि वह अपने लक्ष्यों के प्रति कितना सफल है। यह निरंतर अनुकूलन और सुधार करने की क्षमता ही संगठन को आधुनिक युग की अनिश्चित चुनौतियों और बदलती बाजार परिस्थितियों में जीवित रहने के योग्य बनाती है, जिससे निरंतरता बनी रहती है।

269. (C) विधायिका का वह अधिनियम जिसने इसे सृजित किया
लोक निगम एक स्वायत्त निकाय है, लेकिन इसकी शक्तियों का अंतिम स्रोत वह विशेष अधिनियम है जो विधायिका द्वारा पारित किया गया है। यह अधिनियम ही निगम के उद्देश्यों और सरकार के प्रति इसके उत्तरदायित्व को परिभाषित करता है। निगम के भीतर निदेशक मंडल केवल उसी दायरे में कार्य कर सकते हैं जो इस कानून द्वारा तय किया गया है। यह विधिक आधार ही लोक निगम को सरकारी विभागों से अलग एक स्वतंत्र पहचान प्रदान करता है, जबकि उस पर लोकतांत्रिक नियंत्रण बनाए रखता है ताकि सार्वजनिक धन का सही उपयोग सुनिश्चित हो सके।

270. (C) राज्य के प्रमुख की भूमिका
जब राष्ट्रपति राष्ट्र के प्रतीक और एकता के ध्वजवाहक के रूप में कार्य करते हैं, तो वे राज्य के प्रमुख की भूमिका में होते हैं। इस भूमिका में राजनीतिक शक्तियों के बजाय औपचारिक कर्तव्यों की प्रधानता होती है। इसमें विदेशी गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत करना और राष्ट्रीय उत्सवों की अध्यक्षता करना शामिल है। यह पद राष्ट्र की निरंतरता और सम्मान को दर्शाता है, जो राजनीति के उतार-चढ़ाव से ऊपर होता है। संसदीय प्रणालियों में यह भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण और प्रतीकात्मक होती है, जो राष्ट्र को गौरव और स्थिरता प्रदान करती है।

271. (A) व्यक्तिगत संबंधों का एक नेटवर्क जिसकी आवश्यकता औपचारिक संगठन द्वारा नहीं होती है।
अनौपचारिक संगठन का निर्माण किसी आधिकारिक आदेश से नहीं होता, बल्कि यह कार्यस्थल पर एक साथ काम करने वाले लोगों के बीच स्वाभाविक सामाजिक मेलजोल से उत्पन्न होता है। यह लिखित नियमों के बजाय व्यक्तिगत पसंद और मित्रता के धागों से बंधा होता है। यह संगठन कर्मचारियों की भावनात्मक जरूरतों को पूरा करता है और उनके बीच संचार के एक वैकल्पिक मार्ग के रूप में कार्य करता है। यद्यपि यह आधिकारिक चार्ट पर नहीं दिखता, लेकिन यह संगठन की कार्य संस्कृति और प्रभावशीलता को गहराई से प्रभावित करता है, जो प्रबंधन के लिए विचारणीय है।

272. (C) नीति और कार्यवाही की एकरूपता सुनिश्चित करना।
केंद्रीकरण का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसमें सभी महत्वपूर्ण निर्णय शीर्ष स्तर पर लिए जाते हैं, जिससे पूरे संगठन में एकसमान नीतियों का पालन सुनिश्चित होता है। यह व्यवस्था भ्रम को दूर करती है और यह सुनिश्चित करती है कि संगठन की सभी इकाइयां एक ही मानकों के अनुसार कार्य करें। विशेष रूप से संकट के समय या उन कार्यों में जहाँ कड़ी अनुशासन और कमान की एकता अनिवार्य हो, केंद्रीकरण संसाधनों के सही आवंटन और संगठन पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक सिद्ध होता है, जो कुशलता बढ़ाता है।

273. (B) P-2, Q-1, R-4, S-3
लोक प्रशासन के विभिन्न सिद्धांतों ने इसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फ्रेडरिक टेलर का वैज्ञानिक प्रबंधन मुख्य रूप से कार्य कुशलता और उत्पादकता बढ़ाने पर केंद्रित था। एल्टन मेयो के मानव संबंध सिद्धांत ने सामाजिक कारकों और मानवीय संवेदनाओं को उजागर किया। मैक्स वेबर की नौकरशाही तर्कसंगतता और लिखित नियमों पर आधारित एक आदर्श ढाँचा थी। व्यवस्था दृष्टिकोण ने संगठन को बाहरी वातावरण के साथ अंतःक्रिया करने वाली एक गतिशील इकाई के रूप में देखा। ये सभी विचार मिलकर आधुनिक संगठनात्मक ढांचे और प्रशासन को परिभाषित करते हैं।

274. (C) अधिकतम करता है
हर्बर्ट साइमन ने प्रशासनिक मानव की तुलना शास्त्रीय अर्थशास्त्र के आर्थिक मानव से की थी। आर्थिक मानव के मॉडल के अनुसार, व्यक्ति के पास असीमित जानकारी होती है और वह सदैव अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए इष्टतम विकल्प चुनता है। साइमन ने इस विचार को अव्यावहारिक बताया और तर्क दिया कि प्रशासक अपनी संज्ञानात्मक सीमाओं के कारण अधिकतम करने के बजाय केवल संतोषजनक विकल्प ही चुन पाता है। यह अंतर प्रशासनिक वास्तविकता को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मानवीय सीमाओं को निर्णय प्रक्रिया में स्वीकार करता है।

275. (B) स्टाफ पद
चीफ ऑफ स्टाफ एक महत्वपूर्ण स्टाफ पद है जिसका मुख्य कार्य मुख्य कार्यपालिका को सूचनाओं के प्रबंधन और समन्वय में सहायता देना है। वह सीधे विभागों को आदेश नहीं देता, बल्कि वह कार्यपालिका के समय और संचार प्रवाह को व्यवस्थित करता है। वह एक द्वारपाल की तरह कार्य करता है जो यह तय करता है कि कौन सी सूचनाएं मुख्य कार्यपालिका तक पहुँचेंगी। यह भूमिका शासन की आंतरिक दक्षता बढ़ाने और नेतृत्व को महत्वपूर्ण रणनीतिक कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है, जिससे शासन व्यवस्था सुचारू रूप से कार्य करती है।

NODIA

दिया जाता है। नौकरशाही में हर कार्य के लिए एक जटिल प्रक्रिया अपनानी पड़ती है, जिससे फाइलों के निपटारे में बहुत देरी होती है। यद्यपि ये नियम निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन इनका अत्यधिक और कठोर पालन प्रशासन को जड़ बना देता है। आधुनिक प्रशासनिक सुधारों का मुख्य उद्देश्य इसी लालफीताशाही को कम करना है।

224. (D) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।
यह कहना पूरी तरह गलत है कि विकेंद्रीकरण सदैव अधिक दक्षता की ओर ले जाता है, क्योंकि कभी-कभी यह समन्वय की कमी और संसाधनों की बर्बादी का कारण भी बन सकता है। वास्तव में, केंद्रीकरण या विकेंद्रीकरण की सही मात्रा स्थितिजन्य कारकों पर निर्भर करती है। संगठन का आकार, कार्य की प्रकृति और अधीनस्थों की योग्यता यह तय करते हैं कि अधिकार का वितरण कैसा होना चाहिए। एक सफल संगठन वही है जो अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार इन दोनों प्रणालियों के बीच उचित संतुलन बनाता है।

225. (D) प्रेरक
हेनरी मिंट्ज़बर्ग ने प्रबंधकीय भूमिकाओं को मुख्य रूप से तीन श्रेणियों में विभाजित किया था: पारस्परिक, सूचनात्मक और निर्णयात्मक। इन श्रेणियों के अंतर्गत वे दस विशिष्ट भूमिकाएं, जैसे नेता, संपर्ककर्ता और संसाधन आवंटक की पहचान करते हैं। प्रेरक उनके द्वारा दी गई मूल श्रेणियों में एक स्वतंत्र प्रबंधकीय भूमिका के रूप में सम्मिलित नहीं है। मिंट्ज़बर्ग का यह विश्लेषण यह समझने में मदद करता है कि एक मुख्य कार्यपालिका अपना समय किन वास्तविक गतिविधियों में व्यतीत करती है, जो केवल औपचारिक प्रशासन से व्यापक है।

226. (C) आधुनिक, विकसित और अत्यधिक विभेदित।
फ्रेड रिग्स की शब्दावली में, एक विवर्तित समाज वह है जिसने विकास के उच्चतम स्तर को प्राप्त कर लिया है। ऐसे समाज में कार्यों का स्पष्ट विशेषीकरण होता है और हर कार्य के लिए एक अलग, समर्पित संरचना मौजूद होती है। यहाँ कानून का शासन होता है, भर्ती पूरी तरह योग्यता पर आधारित होती है और प्रशासनिक कार्यों में उच्च स्तर की दक्षता पाई जाती है। रिग्स ने पश्चिमी विकसित राष्ट्रों को इस श्रेणी में रखा था। यह मॉडल प्रिज्मीय या संक्रमणकालीन समाजों के लिए एक मानक की तरह कार्य करता है।

227. (B) पदसोपान का सिद्धांत
पदसोपान का सिद्धांत यह मानता है कि अधिकार का स्रोत संगठन के शीर्ष पर होता है और वहाँ से यह नीचे की ओर क्रमिक रूप से प्रवाहित होता है। प्रत्येक स्तर अपने से ऊपर वाले स्तर से शक्ति प्राप्त करता है और अपने से नीचे वाले स्तर को निर्देश देता है। यह व्यवस्था संगठन में एक पिरामिड जैसी संरचना बनाती है जहाँ आदेशों का प्रवाह व्यवस्थित होता है। यह सिद्धांत कमान की अखंडता बनाए रखने और जवाबदेही तय करने के लिए आधारभूत माना जाता है, जिससे किसी भी संस्थान का अनुशासन सुनिश्चित होता है।

228. (A) नागरिकों की आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायी।
विकास प्रशासन की एक महत्वपूर्ण विशेषता ग्राहक-उन्मुख होना है, जिसका अर्थ है कि प्रशासन का केंद्र बिंदु आम नागरिक और उसकी समस्याएं होनी चाहिए। पारंपरिक नौकरशाही जहाँ केवल नियमों के प्रति वफादार थी, वहीं विकास प्रशासन यह देखता है कि उसकी नीतियों से आम जनता को कितना लाभ मिल रहा है। इसका उद्देश्य प्रशासन को जनता के लिए अधिक सुलभ और संवेदनशील बनाना है। जब नागरिक स्वयं को प्रशासन का केंद्र समझने लगते हैं, तो विकास परियोजनाओं में उनकी सहभागिता और विश्वास स्वतः बढ़ता है।

229. (C) वी. ए. ग्रेक्युनास
वी. ए. ग्रेक्युनास ने संगठन के सिद्धांतों में एक महत्वपूर्ण गणितीय विश्लेषण प्रस्तुत किया था। उन्होंने समझाया कि जैसे-जैसे एक प्रबंधक के अधीनस्थों की संख्या बढ़ती है, उन अधीनस्थों के बीच होने वाले आपसी संबंधों की संख्या ज्यामितीय रूप से बढ़ती है। ग्रेक्युनास का मानना था कि एक प्रबंधक केवल व्यक्तियों को ही नहीं, बल्कि उनके जटिल समूहों को भी संभालता है। उनके इस शोध ने नियंत्रण के क्षेत्र को सीमित रखने की वैज्ञानिक वकालत की ताकि पर्यवेक्षण की गुणवत्ता और संगठनात्मक समन्वय को बनाए रखा जा सके।

230. (C) परिषद
विश्वविद्यालय का कार्यकारी परिषद संगठन के परिषद रूप का एक आदर्श उदाहरण है। यह एक सामूहिक निकाय है जिसमें विभिन्न विशेषज्ञ, शिक्षाविद और प्रशासक शामिल होते हैं। इसका मुख्य कार्य विश्वविद्यालय की उच्च स्तरीय नीतियां बनाना और महत्वपूर्ण नियुक्तियों पर निर्णय लेना है। यहाँ कोई एक व्यक्ति सर्वोच्च नहीं होता, बल्कि सभी सदस्य मिलकर विचार-विमर्श के माध्यम से सामूहिक रूप से निर्णय लेते हैं। यह प्रणाली निष्पक्षता और विभिन्न दृष्टिकोणों के समावेश को सुनिश्चित करने के लिए बहुत प्रभावी मानी जाती है।

231. (B) अभिविन्यास, दृष्टिकोण और प्राधिकार के प्रकार
लाइन और स्टाफ के बीच तनाव का मुख्य कारण उनके काम करने के अलग-अलग तरीके और शक्तियाँ हैं। लाइन अधिकारी सीधे कार्रवाई करने और आदेश देने के आदी होते हैं, जबकि स्टाफ विशेषज्ञ अधिक विश्लेषणात्मक होते हैं। स्टाफ को अक्सर लगता है कि उनके ज्ञान का सम्मान नहीं हो रहा, जबकि लाइन को लगता है कि स्टाफ के सुझाव अव्यावहारिक हैं। यह वैचारिक मतभेद और अधिकार के स्रोतों में अंतर संगठन के भीतर आपसी सहयोग और समन्वय के लिए एक बड़ी प्रशासनिक चुनौती पैदा करता है।

232. (A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
राजनीति और प्रशासन के बीच का जो सख्त विभाजन वुड्रो विल्सन ने सुझाया था, आधुनिक समय में उसे काफी हद तक अस्वीकार कर दिया गया है। वास्तव में, सरकारी अधिकारी केवल आदेशों का पालन नहीं करते, बल्कि अपनी विशेषज्ञता के माध्यम से नीतियों के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। मंत्री अक्सर जटिल समस्याओं के समाधान के लिए

Click Here to Buy book on Amazon

285. (B) निर्णय लेने को सरल बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानसिक संक्षिप्त मार्ग।
निर्णय लेने की प्रक्रिया में ह्यूरिस्टिक्स वे व्यावहारिक नियम होते हैं जो जटिल समस्याओं का त्वरित समाधान खोजने में मदद करते हैं। चूँकि प्रशासकों के पास असीमित समय नहीं होता, इसलिए वे अपने अनुभव के आधार पर कुछ मानसिक संक्षिप्त मार्ग अपनाते हैं। उदाहरण के लिए, पिछली सफलता के आधार पर निर्णय लेना। हालाँकि ये तरीके निर्णय प्रक्रिया को तेज करते हैं, लेकिन कभी-कभी इनके कारण त्रुटियां भी हो सकती हैं। यह सीमित तर्कसंगतता के भीतर कार्य करने का एक स्वाभाविक मानवीय तरीका है, जो दक्षता बढ़ाने में सहायक है।

286. (A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
लोक प्रशासन का अध्ययन समय के साथ अत्यंत परिष्कृत हुआ है। शुरुआती दौर में यह केवल वैज्ञानिक प्रबंधन तक सीमित था, लेकिन बाद में विद्वानों ने महसूस किया कि प्रशासन केवल नियमों का समूह नहीं है। व्यवहारवादी दृष्टिकोण ने मानवीय मनोविज्ञान को जोड़ा और पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण ने प्रशासन और वातावरण के गहरे संबंधों को स्पष्ट किया। इन नए दृष्टिकोणों ने पुराने यांत्रिक सिद्धांतों के स्थान पर अधिक लचीले और यथार्थवादी सिद्धांतों को स्थापित किया, जिससे यह विषय आधुनिक जटिल प्रशासनिक चुनौतियों को समझने के योग्य बन सका है।

287. (C) मानव संबंध सिद्धांत
मानव संबंध सिद्धांत इस क्रांतिकारी विचार पर आधारित है कि कार्यस्थल केवल एक आर्थिक क्षेत्र नहीं है, बल्कि वह एक सामाजिक व्यवस्था है। एल्टन मेयो ने हाथोर्न प्रयोगों से यह सिद्ध किया कि कर्मचारियों के आपसी संबंध और उनका मनोबल उत्पादकता को गहराई से प्रभावित करते हैं। यह सिद्धांत मानता है कि जब कर्मचारी खुद को एक सहयोगी सामाजिक वातावरण का हिस्सा महसूस करते हैं, तो उनकी कार्यक्षमता और संगठन के प्रति वफादारी में उल्लेखनीय वृद्धि होती है, जो केवल वेतन बढ़ाने से संभव नहीं है। यह मानवीय दृष्टिकोण है।

288. (C) नियंत्रण का विस्तृत क्षेत्र
एक सपाट संगठनात्मक संरचना और नियंत्रण का विस्तृत क्षेत्र एक-दूसरे के पूरक हैं। जब एक प्रबंधक बहुत अधिक संख्या में अधीनस्थों को संभालता है, तो संगठन में ऊपर से नीचे तक प्रबंधन के बहुत कम पदसोपानिक स्तर रह जाते हैं। यह संरचना सूचनाओं के प्रवाह को तेज करती है और नौकरशाही की जटिलता को कम करती है। यह उन आधुनिक संगठनों के लिए बहुत लोकप्रिय है जो लचीलापन चाहते हैं और अपने कर्मचारियों को अधिक स्वायत्तता देकर उन्हें सशक्त बनाना चाहते हैं। इसमें त्वरित निर्णय लेना और संवाद करना सरल होता है।

289. (C) लोक निगम
लोक निगम एक ऐसा अनूठा संगठनात्मक रूप है जिसे एक कानूनी व्यक्ति माना जाता है। इसका अर्थ यह है कि निगम की अपनी स्वतंत्र पहचान होती है, जो इसे बनाने वाली सरकार से अलग है। यह अपने नाम पर अनुबंध कर सकता है और कानूनी विवाद की स्थिति में यह किसी पर केस कर सकता है या कोई इस पर केस कर सकता है। यह विशेषता लोक निगमों को सरकारी विभागों की तुलना में अधिक व्यावसायिक स्थिरता और गरिमा प्रदान करती है, जिससे वे बाजार में एक स्वतंत्र इकाई के रूप में कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से कार्य कर सकते हैं।

290. (B) अधिकार का स्वीकृति सिद्धांत
चेस्टर बर्नार्ड द्वारा प्रतिपादित अधिकार का स्वीकृति सिद्धांत पारंपरिक धारणा को चुनौती देता है। उनके अनुसार, अधिकार केवल पद से ऊपर से नीचे नहीं आता, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि अधीनस्थ उस आदेश को स्वीकार करता है या नहीं। यदि कर्मचारी आदेश को नहीं मानता, तो उस अधिकार का कोई व्यावहारिक मूल्य नहीं रह जाता। एक आदेश तभी प्रभावी होता है जब वह संगठन के हितों के अनुकूल हो और कर्मचारी उसे करने में सक्षम हो। यह सिद्धांत प्रबंधन में अधीनस्थ की सचेत सहमति को केंद्र में रखता है।

NODIA

291. (D) 1, 2 और 3
लाइन और स्टाफ का अंतर संगठनात्मक कार्यक्षमता के लिए आधारभूत है। लाइन एजेंसियां सीधे उन प्राथमिक उद्देश्यों को पूरा करती हैं जिनके लिए संगठन बना है। स्टाफ एजेंसियां विशेषज्ञों के रूप में उन्हें परामर्श और अनुसंधान के माध्यम से सहायता प्रदान करती हैं। आधुनिक प्रशासन की बढ़ती जटिलता के कारण, कभी-कभी यह अंतर धुंधला हो जाता है क्योंकि स्टाफ अधिकारी भी प्रायः वास्तविक निर्णयों को गहराई से प्रभावित करते हैं। ये तीनों स्थितियां संगठन के भीतर कार्यों के जटिल बँटवारे और आपसी निर्भरता को स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं।

292. (C) प्रिज्माटिक-साला मॉडल
फ्रेड रिग्स ने प्रिज्माटिक-साला मॉडल विकसित करने से पहले एग्रेरिया और इंडस्ट्रिया के दो चरम मॉडलों का उपयोग किया था। एग्रेरिया पारंपरिक समाजों को दर्शाता था, जबकि इंडस्ट्रिया विकसित देशों को। बाद में रिग्स ने महसूस किया कि इन दोनों के बीच एक बड़ा क्षेत्र है जहाँ अधिकांश विकासशील देश आते हैं, जिसे उन्होंने प्रिज्माटिक समाज कहा। एग्रेरिया और इंडस्ट्रिया इसी प्रिज्माटिक मॉडल के पूर्ववर्ती चरण थे, जिन्होंने प्रशासनिक अध्ययन में तुलनात्मक दृष्टिकोण को एक नई दिशा प्रदान की और इस विषय को अधिक समृद्ध बनाया।

293. (C) संसद या विधायिका
यद्यपि लोक निगमों को अपने दैनिक कार्यों में स्वायत्तता प्राप्त होती है, लेकिन उन पर अंतिम नियंत्रण संसद या विधायिका का ही होता है। चूँकि लोक निगमों का निर्माण संसद के एक विशेष अधिनियम द्वारा किया जाता है, इसलिए वे अपनी नीतियों और सार्वजनिक धन के उपयोग के लिए सीधे तौर पर विधायिका के प्रति जवाबदेह होते हैं। संसद उनकी वार्षिक रिपोर्टों पर चर्चा कर सकती है और उनके कार्यों की समीक्षा के लिए समितियाँ गठित कर सकती है। यह व्यवस्था सुनिश्चित

करती है कि व्यावसायिक स्वायत्तता के साथ सार्वजनिक उत्तरदायित्व बना रहे।

294. (B) हर्बर्ट साइमन
हर्बर्ट साइमन ने लोक प्रशासन के तथाकथित शास्त्रीय सिद्धांतों की आलोचना करते हुए कहा था कि प्रशासन के प्रत्येक सिद्धांत के लिए एक प्रति-सिद्धांत मौजूद है। उनका तर्क था कि ये सिद्धांत वैज्ञानिक नियमों के बजाय विरोधाभासी कहावतों की तरह हैं। उदाहरण के लिए, यदि पदसोपान दक्षता बढ़ाता है, तो वही पदसोपान संचार को धीमा करके दक्षता कम भी करता है। साइमन ने इन सिद्धांतों को उनकी तार्किक विफलता के कारण नकारा और प्रशासन के अध्ययन में मानव व्यवहार के वैज्ञानिक विश्लेषण पर बल देने की वकालत की थी।

295. (A) P-4, Q-2, R-3, S-1
संगठनों में अक्सर कुछ नकारात्मक प्रवृत्तियाँ जन्म लेती हैं। लालफीताशाही का अर्थ जटिल प्रक्रियाओं का अत्यधिक पालन है। लक्ष्य विस्थापन में नियम ही अंतिम साध्य बन जाते हैं और वास्तविक उद्देश्य गौण हो जाता है। पीटर सिद्धांत बताता है कि व्यक्ति अपनी अक्षमता के स्तर तक पदोन्नत होता रहता है। पार्किंसंस नियम कहता है कि उपलब्ध समय को भरने के लिए कार्य का विस्तार होता रहता है। ये सभी अवधारणाएं संगठनात्मक अकुशलता के कारणों को उजागर करती हैं और हमें प्रशासनिक सुधारों के प्रति सदैव सचेत करती हैं।

296. (B) विचार-विमर्श और प्रतिनिधित्व
बहुल कार्यपालिका उन संस्थाओं के लिए सबसे उपयुक्त होती है जहाँ निर्णयों की गुणवत्ता और उनमें विभिन्न हितों का समावेश होना महत्वपूर्ण होता है। इसमें शक्ति कई सदस्यों के बीच समान रूप से बँटी होती है, जिससे विस्तृत चर्चा और सामूहिक बुद्धिमत्ता को बढ़ावा मिलता है। यह प्रणाली व्यक्तिगत निरंकुशता को रोकने और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए बहुत प्रभावी है। चुनाव आयोग जैसे बोर्ड इसके अच्छे उदाहरण हैं जहाँ सामूहिक निर्णय प्रक्रिया जनहित और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने में सहायता प्रदान करती है, जो अनिवार्य है।

297. (B) यह इंगित करने वाली सूचना कि व्यवस्था को सुधार की आवश्यकता है।
व्यवस्था दृष्टिकोण में नकारात्मक फीडबैक एक सुधारात्मक सूचना है। यह संगठन को यह बताता है कि उसका वर्तमान प्रदर्शन उसके निर्धारित लक्ष्यों या मानकों से भटक गया है। जब कोई व्यवस्था यह सूचना प्राप्त करती है, तो वह अपने इनपुट या प्रक्रियाओं में आवश्यक बदलाव करती है ताकि वह पुनः सही मार्ग पर आ सके। यह तंत्र संगठन को बाहरी वातावरण के साथ संतुलन बनाए रखने और अपनी कार्यप्रणाली को निरंतर सुधारने में मदद करता है। यह आत्म-नियमन की प्रक्रिया संगठन के अस्तित्व और सफलता के लिए अनिवार्य मानी जाती है।

298. (B) एडवर्ड वीडनर
एडवर्ड वीडनर को विकास प्रशासन के सबसे प्रमुख प्रतिपादकों में से एक माना जाता है। उन्होंने ही विकास प्रशासन शब्द को व्यापक पहचान दिलाई और इसे परिवर्तन-उन्मुख प्रणाली के रूप में परिभाषित किया। वीडनर का तर्क था कि विकासशील देशों के प्रशासन को केवल नियम लागू करने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसे सामाजिक-आर्थिक प्रगति के लिए एक सक्रिय उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना चाहिए। उनके विचारों ने लोक प्रशासन के क्षेत्र में एक नया आयाम जोड़ा, जिसने प्रशासन को राष्ट्र निर्माण के उद्देश्यों के प्रति अधिक समर्पित बनाया।

299. (B) एक पदसोपान
जब एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पास 6 प्रत्यक्ष अधीनस्थ होते हैं और कुल 400 कर्मचारी, तो इसका अर्थ है कि संगठन में आदेश की एक स्पष्ट श्रृंखला या पदसोपान मौजूद है। अधिकारी शीर्ष पर है, उसके नीचे प्रबंधक हैं, और उनके नीचे अन्य कर्मचारी विभिन्न स्तरों पर विभाजित हैं। यह संरचना यह सुनिश्चित करती है कि अधिकार ऊपर से नीचे प्रवाहित हों और प्रत्येक व्यक्ति को पता हो कि उसे किसे रिपोर्ट करना है। पदसोपान ही वह ढाँचा है जो इतने बड़े कार्यबल के बीच समन्वय स्थापित करता है और उत्तरदायित्व की रेखाएं स्पष्ट करता है।

300. (B) भ्रम और विरोधाभासी आदेशों से बचना।
आदेश की एकता के सिद्धांत का प्राथमिक उद्देश्य संगठन के भीतर कमान की स्पष्टता और अनुशासन बनाए रखना है। यदि एक कर्मचारी को दो अलग-अलग वरिष्ठों से निर्देश मिलते हैं, तो वह इस असमंजस में पड़ सकता है कि किसका पालन पहले करे, जिससे कार्य में विलंब और मानसिक तनाव पैदा होता है। एक ही अधिकारी होने से कर्मचारी के पास स्पष्ट दिशा-निर्देश होते हैं और वह अपने कार्यों के लिए पूरी तरह से जवाबदेह रहता है। यह सिद्धांत विशेष रूप से बड़े संगठनों में समन्वय स्थापित करने और कार्यक्षमता को अधिकतम करने के लिए अनिवार्य माना जाता है।

www.nodia.in

Downloaded from www.pdf.tube

अध्याय 06
लोक प्रशासन

1. कार्मिक प्रशासन में 'भर्ती' को निम्नलिखित में से कौन सबसे अच्छी तरह परिभाषित करता है?
(A) उच्च उत्तरदायित्वों के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने की प्रक्रिया।
(B) संगठनात्मक रिक्तियों के लिए आवेदकों की खोज करने की प्रक्रिया।
(C) मानकों के विरुद्ध कर्मचारी के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया।
(D) कदाचार के लिए कर्मचारियों पर दंड लगाने की प्रक्रिया।

2. निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें।
कथन I: कार्य-बाह्य (ऑफ-द-जॉब) प्रशिक्षण विधियां कर्मचारी को सामान्य कार्य वातावरण से दूर ले जाती हैं।
कथन II: प्रकोष्ठ प्रशिक्षण (वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग) कार्य-स्थल पर (ऑन-द-जॉब) प्रशिक्षण पद्धति का एक उदाहरण है।
(A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं।
(C) कथन I सत्य है लेकिन कथन II असत्य है।
(D) कथन I असत्य है लेकिन कथन II सत्य है।

3. निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र में पदोन्नति का सिद्धांत नहीं है?
(A) योग्यता का सिद्धांत
(B) वरिष्ठता का सिद्धांत
(C) संरक्षण का सिद्धांत
(D) वरिष्ठता-सह-योग्यता का सिद्धांत

4. किसी संगठन में 'मनोबल' की अवधारणा को सबसे उपयुक्त रूप से किस प्रकार वर्णित किया गया है?
(A) कर्मचारियों की शारीरिक क्षमता और स्वास्थ्य।
(B) कर्मचारी को दिया जाने वाला वेतन और अनुलाभ।
(C) कर्मचारी के विरुद्ध की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई।
(D) कार्य और समूह से प्राप्त होने वाली कुल संतुष्टि।

5. मैक्स वेबर के नौकरशाही के सिद्धांत के संबंध में सही कथन की पहचान करें।
(A) यह करिश्माई सत्ता को संगठनात्मक आदर्श के रूप में महत्व देता है।
(B) यह व्यक्तिगत निष्ठा और संरक्षण पर आधारित प्रणाली को बढ़ावा देता है।
(C) यह तार्किकता और निर्वैयक्तिकता द्वारा परिभाषित एक संरचना है।
(D) यह न्यूनतम औपचारिक नियमों के साथ लचीली संरचनाओं की वकालत करता है।

NODIA

6. निम्नलिखित में से कौन सा 'नकारात्मक' भर्ती का एक रूप है?
(A) राष्ट्रीय समाचार पत्रों में रिक्तियों का विज्ञापन देना।
(B) विशिष्ट क्षेत्रों के उम्मीदवारों तक ही आवेदनों को सीमित करना।
(C) संभावित उम्मीदवारों को खोजने के लिए रोजगार कार्यालयों का उपयोग करना।
(D) वरिष्ठ स्तर के कार्यकारी पदों के लिए प्रतिभा खोज (हेड-हंटिंग)।

7. निम्नलिखित स्थिति पर विचार करें: एक प्रशासक को शहरी अपशिष्ट प्रबंधन के लिए एक नई नीति पर निर्णय लेने की आवश्यकता है। इस प्रक्रिया के प्रारंभिक चरण में नेतृत्व का कौन सा कार्य सबसे महत्वपूर्ण है?
(A) अंतिम नीति को सटीकता के साथ क्रियान्वित करना।
(B) स्वच्छता कर्मचारियों को अधिक परिश्रम के लिए प्रेरित करना।
(C) पिछली नीति के वित्तीय व्यय की लेखापरीक्षा करना।
(D) समस्या को परिभाषित करना और नीति के लिए उद्देश्य निर्धारित करना।

8. एक लोक सेवक और एक मंत्री के बीच संबंधों के बारे में गलत कथन की पहचान करें।
(A) नीति निर्माण में लोक सेवक के पास अंतिम अधिकार होता है।
(B) मंत्री विभाग के लिए राजनीतिक रूप से उत्तरदायी होता है।
(C) लोक सेवक अनामिक और तटस्थ सलाह प्रदान करता है।
(D) लोक सेवक मंत्री के नीतिगत निर्णयों को लागू करता है।

9. एक संगठनात्मक पदानुक्रम में 'अधोमुखी संचार' में आमतौर पर निम्नलिखित में से क्या शामिल होता है?
(A) सुझाव योजनाएं
(B) शिकायत रिपोर्ट
(C) नीतिगत निर्देश और आदेश
(D) कर्मचारी मनोवृत्ति सर्वेक्षण

10. सूची I को सूची II के साथ सुमेलित करें और सही उत्तर चुनें।
सूची I:
P. लूट पद्धति (स्पॉइल्स सिस्टम)
Q. योग्यता प्रणाली

59. 'लोकपाल' और 'लोकायुक्त' के बीच मुख्य अंतर यह है कि:
(A) लोकपाल भ्रष्टाचार से निपटता है जबकि लोकायुक्त अक्षमता से।
(B) लोकपाल एक न्यायिक निकाय है जबकि लोकायुक्त एक कार्यकारी निकाय है।
(C) लोकपाल राज्य स्तर पर कार्य करता है जबकि लोकायुक्त राष्ट्रीय स्तर पर।
(D) लोकपाल राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करता है जबकि लोकायुक्त राज्य स्तर पर।

60. अंतरराष्ट्रीय संगठनों द्वारा अक्सर उद्धृत 'सुशासन' के स्तंभों में से कौन सा नहीं है?
(A) जवाबदेही
(B) गोपनीयता
(C) भागीदारी
(D) विधि का शासन

61. 'ग्रेपवाइन' (जनश्रुति) किसका एक प्रकार है?
(A) औपचारिक संचार माध्यम।
(B) अधोमुखी संचार।
(C) अनौपचारिक संचार माध्यम।
(D) उर्ध्वमुखी संचार।

62. कार्मिक प्रशासन में 'पद वर्गीकरण' में शामिल है:
(A) केवल वरिष्ठता के वर्षों के आधार पर कर्मचारियों की रैंकिंग करना।
(B) कर्मचारियों को उनके राजनीतिक झुकाव के आधार पर वर्गीकृत करना।
(C) व्यक्तिगत पक्षपात के आधार पर पदानुक्रम बनाना।
(D) कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के आधार पर पदों का समूहन करना।

63. किस आलोचक ने तर्क दिया कि नौकरशाही 'लक्ष्य विस्थापन' (गोल डिस्प्लेसमेंट) की ओर ले जाती है?
(A) रॉबर्ट के. मर्टन
(B) मैक्स वेबर
(C) हर्बर्ट साइमन
(D) चेस्टर बर्नार्ड

64. एक लोक सेवक जो व्यक्तिगत या राजनीतिक पूर्वाग्रह के बिना तथ्यों और नियमों के आधार पर मंत्री को सलाह देता है, वह किस सिद्धांत का प्रदर्शन कर रहा है?
(A) अनामिकता
(B) तटस्थता
(C) प्रतिबद्धता
(D) उत्तरदायित्व

65. 'मद-वार' (लाइन-आइटम) बजट की आलोचना मुख्य रूप से किस लिए की जाती है?
(A) परिणामों और निष्पादन पर अत्यधिक बल देने के लिए।
(B) सरकार वास्तव में क्या कर रही है, इसके बारे में जानकारी न देने के लिए।
(C) अत्यधिक जटिल और तैयार करने में कठिन होने के लिए।
(D) प्रतिवर्ष शून्य-आधारित औचित्य की आवश्यकता के लिए।

66. विकास प्रशासन के संदर्भ में नौकरशाही के सामने सबसे महत्वपूर्ण चुनौती क्या है?
(A) एक कठोर, नियम-बद्ध संरचना जो नवाचार को रोकती है।
(B) योग्य कर्मियों की अत्यधिक प्रचुरता।
(C) एक अत्यधिक विकेंद्रीकृत निर्णय लेने की प्रक्रिया।
(D) नागरिक संतुष्टि पर अत्यधिक ध्यान।

67. यदि सूचना किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है, तो जन सूचना अधिकारी (PIO) को इसे कितने समय के भीतर उपलब्ध कराना होगा?
(A) 30 दिन
(B) 45 दिन
(C) 48 घंटे
(D) 90 दिन

68. 'ओम्बुड्समैन' की अवधारणा किस देश में उत्पन्न हुई?
(A) यूनाइटेड किंगडम
(B) फ्रांस
(C) संयुक्त राज्य अमेरिका
(D) स्वीडन

69. निम्नलिखित में से कौन 'कर्मचारी मनोबल' का सबसे अच्छा वर्णन करता है?
(A) एक कर्मचारी के पास पेशेवर कौशल का स्तर।
(B) कार्य और वातावरण के प्रति मानसिक और भावनात्मक दृष्टिकोण।
(C) संगठनात्मक पदानुक्रम में कर्मचारी का औपचारिक पद।
(D) क्षेत्रीय कर्तव्यों के लिए आवश्यक शारीरिक स्वास्थ्य।

70. सूची I को सूची II के साथ सुमेलित करें और सही उत्तर चुनें।
सूची I:
P. भर्ती
Q. प्रशिक्षण
R. पदोन्नति
S. अनुशासन
सूची II:
1. उच्च पद पर उन्नति
2. अवांछनीय व्यवहार में सुधार करना
3. उपयुक्त उम्मीदवारों को आकर्षित करना
4. कौशल और ज्ञान को बढ़ाना
(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-3, Q-4, R-1, S-2
(C) P-3, Q-1, R-4, S-2
(D) P-2, Q-4, R-1, S-3

Click Here to Buy book on Amazon

22. मैक्स वेबर के नौकरशाही मॉडल की आलोचना निम्नलिखित में से किस कारण से की जाती है?
(A) यह मानवीय संबंधों और अनौपचारिक समूहों पर अत्यधिक बल देता है।
(B) यह लक्ष्य विस्थापन की ओर ले जाता है जहाँ नियम साध्य बन जाते हैं।
(C) यह एक अत्यधिक लचीली और अनुकूलन योग्य प्रणाली को बढ़ावा देता है।
(D) यह करिश्माई नेताओं को बहुत अधिक शक्ति देता है।

23. 'वरिष्ठता के सिद्धांत' पर आधारित 'पदोन्नति' मुख्य रूप से किसे महत्व देती है?
(A) कर्मचारी की शैक्षणिक योग्यता।
(B) कर्मचारी की कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट।
(C) वरिष्ठों के साथ कर्मचारी के व्यक्तिगत संबंध।
(D) किसी विशेष श्रेणी में कर्मचारी की सेवा की अवधि।

24. निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें।
कथन I: किसी संगठन में 'अनुशासन' विशेष रूप से कर्मचारियों को दंडित करने के कार्य को संदर्भित करता है।
कथन II: अनुशासनात्मक कार्रवाई का उद्देश्य सुधारात्मक है, न कि दंडात्मक।
(A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं।
(C) कथन I असत्य है लेकिन कथन II सत्य है।
(D) कथन I सत्य है लेकिन कथन II असत्य है।

25. एक विशिष्ट अनुशासनात्मक प्रक्रिया के निम्नलिखित चरणों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें:
1. आरोप-पत्र (चार्ज-शीट) जारी करना।
2. प्रारंभिक जांच।
3. दंड अधिरोपित करना।
4. औपचारिक जांच करना।
(A) 1, 2, 4, 3
(B) 2, 1, 4, 3
(C) 2, 4, 1, 3
(D) 1, 4, 2, 3

26. एफ.एम. मार्क्स के अनुसार, किस प्रकार की नौकरशाही की विशेषता वर्ग या सामाजिक स्थिति के आधार पर भर्ती है?
(A) जातीय नौकरशाही
(B) अभिभावक नौकरशाही
(C) संरक्षण नौकरशाही
(D) योग्यता नौकरशाही

27. भारत जैसे विकासशील देश में नौकरशाही के लिए विकास की चुनौतियों में क्या शामिल नहीं है?
(A) अत्यधिक केंद्रीकरण और प्रक्रियात्मक कठोरता।
(B) प्रतिबद्धता की कमी और दृष्टिकोण संबंधी समस्याएं।
(C) भ्रष्टाचार और जवाबदेही का अभाव।
(D) संसाधनों और प्रशिक्षित जनशक्ति की प्रचुरता।

28. 'निष्पादन बजट' (परफॉर्मेंस बजटिंग) की अवधारणा किस पर केंद्रित है?
(A) व्यय की वस्तुएं जैसे वेतन और आपूर्ति।
(B) किए गए कार्य, कार्यक्रम और गतिविधियाँ।
(C) बजट की प्रत्येक मद को प्रारंभ से न्यायोचित ठहराना।
(D) विभागों की राजनीतिक संबद्धता।

29. प्रशासन के संदर्भ में 'शिकायत निवारण' का अर्थ है:
(A) नए कर्मचारियों की भर्ती की प्रक्रिया।
(B) हितधारकों की शिकायतों को हल करने की प्रणाली।
(C) मौजूदा कर्मियों को प्रशिक्षित करने की प्रक्रिया।
(D) विदेश नीति के उद्देश्यों का निर्धारण।

30. भारत में लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 मुख्य रूप से किसकी सिफारिशों के आधार पर लागू किया गया था?
(A) सरकारिया आयोग।
(B) पुंछी आयोग।
(C) द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग।
(D) प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग।

31. एक नौकरशाही संरचना में संचार की एक प्रमुख विशेषता किस पर इसका बल है?
(A) लिखित और औपचारिक माध्यम।
(B) मौखिक और अनौपचारिक माध्यम।
(C) जनश्रुति और अफवाहें।
(D) भावनात्मक और व्यक्तिगत अपील।

32. एक मंत्री और एक लोक सेवक के बीच के संबंध को सबसे उपयुक्त रूप में इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है:
(A) एक स्वामी और एक सेवक।
(B) एक राजनीतिक प्रमुख और एक स्थायी कार्यपालिका।
(C) एक पेशेवर और एक मुवक्किल।
(D) निर्णय लेने में दो समान भागीदार।

33. निम्नलिखित में से कौन 'अप्रत्यक्ष' भर्ती का एक प्रकार है?
(A) समाचार पत्रों में विज्ञापन देना।
(B) आंतरिक पदोन्नति।
(C) परिसर साक्षात्कार (कैंपस इंटरव्यू)।
(D) सीधे साक्षात्कार (वॉक-इन इंटरव्यू)।

34. निम्नलिखित परिदृश्य के आधार पर सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें: एक लोक सेवक सेवा लक्ष्यों को प्राप्त करने के बजाय व्यक्तिगत जोखिम से बचने के लिए नियमों के शाब्दिक पाठ का कड़ाई से पालन करता है। यह किसका उदाहरण है?
(A) नौकरशाही में लक्ष्य विस्थापन।
(B) उच्च मनोबल और अभिप्रेरणा।
(C) प्रभावी निर्णय-प्रक्रिया।
(D) योग्यता सिद्धांत की सफलता।

Downloaded from www.pdf.tube

83. निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक प्रशासन में भ्रष्टाचार का एक उदाहरण है?
(A) एक पुलिस अधिकारी किसी मामले को सुलझाने के लिए अतिरिक्त समय कार्य कर रहा है।
(B) एक शिक्षक कमजोर छात्रों को अतिरिक्त कक्षाएं प्रदान कर रहा है।
(C) एक लिपिक फाइल को शीघ्र बढ़ाने के लिए रिश्वत की मांग कर रहा है।
(D) एक चिकित्सक सरकारी अस्पताल में रोगी का उपचार कर रहा है।

84. लोकायुक्त की संस्था सबसे पहले किस राज्य में स्थापित की गई थी?
(A) राजस्थान
(B) उत्तर प्रदेश
(C) केरल
(D) महाराष्ट्र

85. निम्नलिखित प्रकार के बजटों को उनके वैचारिक विकास के कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें:
1. निष्पादन बजट
2. मद-वार बजट
3. शून्य-आधारित बजट
4. नियोजन, प्रोग्रामिंग, बजटिंग प्रणाली (PPBS)
(A) 2, 1, 4, 3
(B) 1, 2, 3, 4
(C) 2, 4, 1, 3
(D) 3, 4, 1, 2

86. कर्मचारी मनोबल सुधारने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त उपाय है?
(A) अनुशासनात्मक कार्रवाइयां बढ़ाना।
(B) सकारात्मक कार्य वातावरण और प्रोत्साहन प्रदान करना।
(C) नियमों और विनियमों को अधिक कठोर बनाना।
(D) कर्मचारी शिकायतों के माध्यमों को कम करना।

87. टेनेसी वैली अथॉरिटी (TVA) के फिलिप सेल्ज़निक के अध्ययन ने किस अवधारणा पर प्रकाश डाला?
(A) प्रशिक्षित अक्षमता।
(B) अल्पतंत्र का लौह नियम।
(C) नौकरशाही विकृति (ब्यूरो-पैथोलॉजी)।
(D) औपचारिक और अनौपचारिक सह-वरण (को-ऑप्टेशन)।

88. मंत्री और लोक सेवक के बीच संबंध किसका एक पहलू है?
(A) राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका के संबंध।
(B) न्यायिक पुनरावलोकन।
(C) संघ-राज्य संबंध।
(D) अंतर-विभागीय समन्वय।

89. स्वतंत्रता के बाद भारत में अपनाई गई 'विकास योजना' की एक प्रमुख मान्यता क्या थी?
(A) केवल बाजार ही न्यायसंगत विकास ला सकता है।
(B) विकास के लिए विदेशी सहायता अनावश्यक है।
(C) आर्थिक विकास के मार्गदर्शन में राज्य की केंद्रीय भूमिका है।
(D) विकास प्रक्रिया में नौकरशाही की कोई भूमिका नहीं है।

NODIA

90. 'लेखापरीक्षा' (ऑडिट) शब्द लैटिन शब्द 'ऑडिरे' (Audire) से लिया गया है, जिसका अर्थ है:
(A) सुनना
(B) लिखना
(C) जाँचना
(D) गणना करना

91. प्रशासन में 'पारदर्शिता' की अवधारणा का तात्पर्य है कि:
(A) सभी सरकारी फाइलों को गुप्त रखा जाना चाहिए।
(B) केवल वरिष्ठ अधिकारियों की ही सूचना तक पहुँच हो।
(C) नागरिकों को प्रशासनिक कार्यों पर प्रश्न उठाने का कोई अधिकार नहीं है।
(D) उपलब्ध सूचना के साथ नियमों का पालन करते हुए निर्णय लिए जाते हैं।

92. लोकपाल एक बहु-सदस्यीय निकाय है। इसके सदस्यों की संरचना क्या है?
(A) 50% सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों और महिलाओं में से होंगे।
(B) (A) और (D) दोनों सही हैं।
(C) सभी सदस्य सेवानिवृत्त न्यायाधीश होने चाहिए।
(D) 50% सदस्य न्यायिक सदस्य होंगे।

93. निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें।
कथन I: सीधी भर्ती लोक सेवा में नवीन दृष्टिकोण और व्यापक विकल्प लाती है।
कथन II: अप्रत्यक्ष भर्ती (पदोन्नति) अंतर्प्रजनन (इनब्रीडिंग) और गतिहीनता की ओर ले जा सकती है।
(A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं।
(C) कथन I सत्य है लेकिन कथन II असत्य है।
(D) कथन I असत्य है लेकिन कथन II सत्य है।

94. एफ.एम. मार्क्स द्वारा वर्णित 'संरक्षण नौकरशाही' किसका पर्याय है?
(A) योग्यता प्रणाली
(B) अभिभावक प्रणाली
(C) जातीय प्रणाली
(D) लूट पद्धति (स्पॉइल्स सिस्टम)

95. संचार प्रक्रिया में, 'संकेतीकरण' (एन्कोडिंग) किसे संदर्भित करता है?
(A) प्रेषक द्वारा किसी विचार को प्रेषण योग्य संदेश में

(C) सामूहिक सौदेबाजी
(D) अनौपचारिक सामाजिक मेलजोल

47. भारतीय प्रशासन के संदर्भ में 'सतर्कता आयोग' का प्राथमिक उद्देश्य है:
(A) भ्रष्टाचार का मुकाबला करना और प्रशासन में सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करना।
(B) सरकारी नीतियों को बढ़ावा देना।
(C) लोक सेवाओं के लिए भर्ती करना।
(D) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के खातों की लेखापरीक्षा करना।

48. वह बजट जिसमें पिछले वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान वर्ष के बजट के आधार के रूप में लिया जाता है, कहलाता है:
(A) निष्पादन बजट
(B) वृद्धिशील बजट
(C) शून्य-आधारित बजट
(D) जेंडर बजट

49. प्रबंधकीय ग्रिड के अनुसार, कौन सी नेतृत्व शैली लोगों के प्रति उच्च सरोकार लेकिन उत्पादन के प्रति कम सरोकार दिखाती है?
(A) दरिद्र प्रबंधन
(B) कंट्री क्लब प्रबंधन
(C) टीम प्रबंधन
(D) अधिकार-अनुपालन प्रबंधन

50. भारत में लोकपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. यह सर्वोच्च न्यायालय के समान शक्तियों वाला एक संवैधानिक निकाय है।
2. प्रधानमंत्री लोकपाल के अधिकार क्षेत्र से पूर्णतः बाहर हैं।
3. इसमें एक अध्यक्ष और अधिकतम आठ सदस्य होते हैं।
उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) केवल 3
(B) केवल 1 और 2
(C) केवल 2 और 3
(D) 1, 2 और 3

51. भविष्य में उच्च पद संभालने के लिए किसी कर्मचारी को तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है:
(A) भर्ती
(B) कार्य विस्तार
(C) उत्तराधिकार नियोजन
(D) अनुशासनात्मक कार्रवाई

52. नौकरशाही में रॉबर्ट मर्टन की 'प्रशिक्षित अक्षमता' की अवधारणा किसे संदर्भित करती है?
(A) नौकरशाहों की कार्य करने की शारीरिक असमर्थता।
(B) सिविल सेवा के नए रंगरूटों में बुनियादी शिक्षा का अभाव।
(C) आधुनिक तकनीकी समाधानों को लागू करने में विफलता।
(D) पिछला प्रशिक्षण और कौशल जो नई परिस्थितियों में अनुकूलन में बाधा डालते हैं।

53. मैक्स वेबर द्वारा 'लौह पिंजरा' (आयरन केज) वाक्यांश का प्रयोग किसे वर्णित करने के लिए किया गया था?
(A) आधुनिक पूंजीवाद की मुक्तिदायी क्षमता।
(B) अत्यधिक संरचित कानूनी प्रणाली के लाभ।
(C) बढ़ती तार्किकता और नियम-आधारित नियंत्रण।
(D) संगठनों में दंडात्मक अनुशासन की प्रणाली।

54. सरकारी नौकरी के लिए एक आवेदक का मूल्यांकन लिखित परीक्षा, साक्षात्कार और शारीरिक परीक्षण के आधार पर किया जाता है। यह किसका उदाहरण है?
(A) लूट पद्धति
(B) योग्यता प्रणाली
(C) जातीय प्रणाली
(D) संरक्षण प्रणाली

55. निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें।
कथन I: नेतृत्व लक्ष्यों की दिशा में कार्य करने के लिए दूसरों को प्रभावित करने की प्रक्रिया है।
कथन II: सभी प्रबंधक नेता होते हैं।
(A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं।
(C) कथन I सत्य है लेकिन कथन II असत्य है।
(D) कथन I असत्य है लेकिन कथन II सत्य है।

56. संचार प्रक्रिया में 'शोर' (नॉइज़) को सबसे उपयुक्त रूप में परिभाषित किया गया है:
(A) कोई भी कारक जो संदेश को विकृत करता है या उसमें हस्तक्षेप करता है।
(B) प्राप्तकर्ता से प्राप्त प्रतिपुष्टि।
(C) वह माध्यम जिसके द्वारा संदेश भेजा जाता है।
(D) वह मूल विचार जिसे प्रेषक संप्रेषित करना चाहता है।

57. भारतीय प्रशासन पर उदारीकरण के प्रभाव में किस पर अधिक बल दिया गया है?
(A) राज्य का एकाधिकार और लाइसेंसिंग प्रणाली।
(B) विभाग द्वारा संचालित उद्योगों का विस्तार।
(C) सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP)।
(D) केंद्रीकृत पंचवर्षीय योजनाएं।

58. बजट के विभिन्न स्वरूपों के बारे में सही कथन की पहचान करें।
(A) मद-वार बजट - व्यय की मदों पर नियंत्रण पर केंद्रित
(B) निष्पादन बजट - केवल आगत (इनपुट) पर केंद्रित
(C) शून्य-आधारित बजट - वृद्धिशील दृष्टिकोण
(D) कार्यक्रम बजट - उद्देश्यों की अनदेखी

Click Here to Buy book on Amazon

R. पद वर्गीकरण
S. सामूहिक सौदेबाजी

सूची II:
1. कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन
2. प्रबंधन और प्रतिनिधियों के बीच बातचीत
3. राजनीतिक संबद्धता के आधार पर भर्ती
4. क्षमता और योग्यता के आधार पर भर्ती

(A) P-3, Q-4, R-1, S-2
(B) P-4, Q-3, R-2, S-1
(C) P-3, Q-1, R-4, S-2
(D) P-2, Q-4, R-1, S-3

11. एक 'शून्य-आधारित बजट' (ZBB) के लिए प्रत्येक विभागीय कार्यक्रम की आवश्यकता होती है:
(A) प्रतिवर्ष एक निश्चित प्रतिशत की वृद्धि करना।
(B) पिछले वर्ष के आवंटन के आधार पर वित्तपोषित करना।
(C) हर पांच साल में केवल एक बार लेखापरीक्षा करना।
(D) प्रत्येक वर्ष इसकी संपूर्णता में औचित्य सिद्ध करना।

12. भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम का मुख्य उद्देश्य किसे बढ़ावा देना है?
(A) नौकरशाही में भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद।
(B) सार्वजनिक प्राधिकरण में पारदर्शिता और जवाबदेही।
(C) सरकार के सभी नियमित कार्यों में गोपनीयता।
(D) कनिष्ठ लोक सेवकों की विवेकाधीन शक्ति।

13. 'ओम्बुड्समैन' (लोकपाल/लोकायुक्त) की प्राथमिक भूमिका क्या है?
(A) न्यायालय में अपराधियों पर मुकदमा चलाना।
(B) देश का वार्षिक बजट तैयार करना।
(C) कुप्रशासन के विरुद्ध शिकायतों की जांच करना।
(D) राष्ट्र के सशस्त्र बलों की कमान संभालना।

14. 'ब्यूरोक्रेसी' (नौकरशाही) शब्द सबसे पहले किसके द्वारा गढ़ा गया था?
(A) मैक्स वेबर
(B) वुडरो विल्सन
(C) एफ.डब्ल्यू. टेलर
(D) विन्सेंट डी गोर्ने

15. निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन शामिल हैं, एक को कथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है। सही उत्तर चुनिए।
कथन (A): कर्मचारियों के बीच उच्च मनोबल अक्सर उच्च उत्पादकता से संबंधित होता है।
कारण (R): मनोबल एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है जो सहयोग करने की इच्छा को निर्धारित करती है।
(A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(D) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

16. निम्नलिखित में से कौन 'कार्य-स्थल पर' (ऑन-द-जॉब) प्रशिक्षण पद्धति का एक उदाहरण है?
(A) व्याख्यान विधि
(B) कोचिंग (मार्गदर्शन)
(C) मामला अध्ययन (केस स्टडी) विधि
(D) संवेदनशीलता प्रशिक्षण

17. भारत में लोक प्रशासन पर उदारीकरण के प्रभाव के कारण क्या परिवर्तन हुआ है?
(A) सार्वजनिक क्षेत्र के आकार और कार्यक्षेत्र में वृद्धि।
(B) राज्य की भूमिका में एक सुगमकर्ता और नियामक के रूप में बदलाव।
(C) पारदर्शिता के महत्व में कमी।
(D) नौकरशाही का पूर्ण उन्मूलन।

18. वित्तीय प्रशासन के संदर्भ में, 'लेखापरीक्षा' (ऑडिट) मुख्य रूप से किस उद्देश्य को पूरा करती है?
(A) यह सुनिश्चित करना कि व्यय नियमों और उचित मितव्ययिता के अनुरूप हो।
(B) अगले वित्तीय वर्ष के लिए बजट तैयार करना।
(C) विभिन्न सरकारी विभागों को धन वितरित करना।
(D) आगामी वर्ष के लिए कर की दरें तय करना।

19. गलत युग्म की पहचान करें।
(A) लोकपाल - केंद्रीय स्तर पर भ्रष्टाचार रोकने वाली संस्था।
(B) लोकायुक्त - राज्य स्तर पर भ्रष्टाचार रोकने वाली संस्था।
(C) सी.वी.सी. - शिकायत निवारण के लिए एक संवैधानिक निकाय।
(D) ओम्बुड्समैन - सबसे पहले स्वीडन में स्थापित संस्था।

20. 'सुशासन' के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. यह नागरिक भागीदारी और विधि के शासन पर बल देता है।
2. यह केवल किसी देश की आर्थिक वृद्धि से संबंधित है।
3. यह प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देता है।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3

21. नेतृत्व का कौन सा सिद्धांत बताता है कि नेता पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते?
(A) व्यवहारवादी सिद्धांत
(B) स्थितिजन्य सिद्धांत
(C) विशेषक (ट्रेट) सिद्धांत
(D) परिवर्तनकारी सिद्धांत

NODIA

71. नेतृत्व का 'स्थितिजन्य सिद्धांत' इस बात पर जोर देता है कि एक नेता की प्रभावशीलता किस पर निर्भर करती है?
(A) नेता के जन्मजात गुणों पर।
(B) नेता द्वारा प्रदर्शित व्यवहार पर।
(C) नेता के करिश्माई व्यक्तित्व पर।
(D) परिस्थिति और अनुयायियों की परिपक्वता पर।

72. भारत में उदारीकरण के बाद नियामक निकायों का उदय राज्य की भूमिका में किस प्रकार के बदलाव को दर्शाता है?
(A) खेने (रोइंग) के बजाय दिशा देना (स्टीयरिंग)।
(B) वस्तुओं के प्रत्यक्ष उत्पादन में वृद्धि।
(C) केंद्रीकृत आर्थिक नियोजन।
(D) बाजार हस्तक्षेप के सभी रूपों को समाप्त करना।

73. 'सामाजिक लेखापरीक्षा' (सोशल ऑडिट) का प्राथमिक उद्देश्य किसे बढ़ाना है?
(A) वित्तीय लाभप्रदता।
(B) राजनीतिक नियंत्रण।
(C) जवाबदेही और पारदर्शिता।
(D) नौकरशाही गोपनीयता।

74. भारत में बजट प्रक्रिया के संबंध में गलत कथन की पहचान करें।
(A) राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार कर सकती है।
(B) बजट वित्त मंत्री द्वारा संसद में पेश किया जाता है।
(C) बजट प्रस्तुतीकरण और अनुदान की मांगों पर मतदान के चरणों से गुजरता है।
(D) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक व्यय के पश्चात खातों की लेखापरीक्षा करता है।

75. निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन शामिल हैं, एक को कथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है। सही उत्तर चुनिए।
कथन (A): सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक शक्तिशाली उपकरण है।
कारण (R): यह नागरिकों को सरकारी कार्यों और निर्णयों की जांच करने का अधिकार देता है।
(A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(D) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

76. "भर्ती एक सकारात्मक प्रक्रिया है जबकि चयन एक नकारात्मक प्रक्रिया है।" इस कथन का तात्पर्य है कि:
(A) भर्ती अच्छी है और चयन बुरा है।
(B) भर्ती कइयों को आकर्षित करती है जबकि चयन अनुपयुक्तों को बाहर कर देता है।
(C) भर्ती निचले स्तर के पदों के लिए है और चयन उच्च स्तर के लिए है।
(D) भर्ती सरकार द्वारा की जाती है और चयन निजी फर्मों द्वारा।

77. मैक्स वेबर के अनुसार, किस प्रकार की सत्ता आधुनिक नौकरशाही का आधार बनती है?
(A) पारंपरिक सत्ता
(B) करिश्माई सत्ता
(C) विधिक-तार्किक सत्ता
(D) राजनीतिक सत्ता

78. एक अनुकरणित वातावरण में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम, जो वास्तविक कार्य वातावरण के सदृश होता है, कहलाता है:
(A) कार्य परिवर्तन (जॉब रोटेशन)
(B) कोचिंग (मार्गदर्शन)
(C) सम्मेलन विधि
(D) प्रकोष्ठ (वेस्टिब्यूल) प्रशिक्षण

79. एक लोक सेवक की 'अनामिकता' के सिद्धांत का अर्थ है कि वह:
(A) नीतिगत परिणामों के लिए सार्वजनिक रूप से प्रशंसा या दोष का पात्र नहीं होता है।
(B) कुछ नीतियों पर कार्य करने से मना कर सकता है।
(C) उसे गुप्त रहना चाहिए और अपनी पहचान उजागर नहीं करनी चाहिए।
(D) किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है।

80. निर्णय लेने में नेतृत्व की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. एक नेता की प्राथमिक भूमिका किसी भी निर्णय लेने से बचना है।
2. प्रभावी नेता भागीदारी को प्रोत्साहित करके समूह निर्णय लेने की सुविधा प्रदान करते हैं।
3. नेतृत्व शैली निर्णयों की गुणवत्ता और स्वीकृति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती है।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3

81. किसी संगठन में 'क्षैतिज संचार' किसके बीच होता है?
(A) एक वरिष्ठ और एक अधीनस्थ।
(B) एक ही पदानुक्रमित स्तर पर कार्यरत कर्मचारी।
(C) सी.ई.ओ. और निदेशक मंडल।
(D) संगठन और उसके बाहरी हितधारक।

82. नौकरशाही के लिए विकास की चुनौती अक्सर किसके बीच संघर्ष की विशेषता होती है?
(A) मानकीकृत प्रक्रियाएं और लचीलेपन की आवश्यकता।
(B) नियमन के लक्ष्य और संवर्धन के लक्ष्य।
(C) शहरी अभिजात वर्ग और ग्रामीण निर्धनों के हित।
(D) विभिन्न सरकारी विभागों के उद्देश्य।

Downloaded from www.pdf.tube

35. निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें।
कथन I: भर्ती की 'लूट पद्धति' प्रशासन पर राजनीतिक नियंत्रण को सुदृढ़ करती है।
कथन II: भर्ती की 'योग्यता प्रणाली' का उद्देश्य सिविल सेवा में राजनीतिक तटस्थता और सक्षमता सुनिश्चित करना है।
(A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं।
(C) कथन I सत्य है लेकिन कथन II असत्य है।
(D) कथन I असत्य है लेकिन कथन II सत्य है।

36. निम्नलिखित में से कौन मैक्स वेबर की आदर्श नौकरशाही की विशेषता नहीं है?
(A) सत्ता का पदानुक्रम
(B) अमूर्त नियमों की प्रणाली
(C) नियमों को लागू करने में निर्वैयक्तिकता
(D) व्यक्तिगत और भावनात्मक संबंध

37. प्रशिक्षण की 'मामला अध्ययन' (केस-स्टडी) विधि किसके विकास के लिए सबसे उपयुक्त है?
(A) शारीरिक कौशल।
(B) नियमों को रटना।
(C) विश्लेषणात्मक और समस्या-समाधान क्षमताएं।
(D) शारीरिक सहनशक्ति।

38. सूचना के अधिकार (RTI) द्वारा प्रशासन की निम्नलिखित में से किस समस्या का प्रत्यक्ष समाधान किया जाता है?
(A) वित्तीय संसाधनों की कमी।
(B) पारदर्शिता का अभाव।
(C) तकनीकी विशेषज्ञता की कमी।
(D) पदानुक्रमित संरचना का अभाव।

39. 'सुशासन' शब्द किस पर आधारित 1989 की विश्व बैंक की रिपोर्ट के बाद लोकप्रिय हुआ?
(A) दक्षिण एशिया।
(B) लैटिन अमेरिका।
(C) पूर्वी यूरोप।
(D) उप-सहारा अफ्रीका।

40. सूची I को सूची II के साथ सुमेलित करें और सही उत्तर चुनें।
सूची I:
P. रॉबर्ट मर्टन
Q. एल्विन गोल्डनर
R. फिलिप सेल्ज़निक
S. मिशेल क्रोज़ियर
सूची II:
1. नौकरशाही का द्विभाजन (दंड-केंद्रित/प्रतिनिधि)
2. लक्ष्य विस्थापन और प्रशिक्षित अक्षमता
3. नौकरशाही का दुष्चक्र और शक्ति की परिघटना
4. सह-वरण (को-ऑप्टेशन) और उप-इकाई विचारधाराएं
(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-2, Q-1, R-4, S-3
(C) P-3, Q-1, R-4, S-2
(D) P-2, Q-3, R-4, S-1

41. 'विकास योजना' की प्रमुख चुनौतियों में से एक है:
(A) नियोजित लक्ष्यों और वास्तविक उपलब्धियों के बीच संतुलन बनाना।
(B) अत्यधिक सार्वजनिक भागीदारी का होना।
(C) विशिष्ट कर्मियों की आवश्यकता को समाप्त करना।
(D) एक केंद्रीकृत योजना प्राधिकरण की अनुपस्थिति।

42. भारत में, सरकारी खातों की लेखापरीक्षा करना किसकी संवैधानिक जिम्मेदारी है?
(A) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG)।
(B) वित्त मंत्री।
(C) भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर।
(D) प्रधानमंत्री कार्यालय।

43. एक नवनियुक्त लोक सेवक को कार्य की जिम्मेदारियों को सीखने के लिए एक अनुभवी वरिष्ठ अधिकारी के साथ नियुक्त किया जाता है। प्रशिक्षण की इस पद्धति को किस रूप में जाना जाता है?
(A) प्रकोष्ठ (वेस्टिब्यूल) प्रशिक्षण
(B) प्रशिक्षुता (अपेंटिसशिप)
(C) मामला अध्ययन (केस स्टडी)
(D) कोचिंग (मार्गदर्शन)

44. 'मनोबल' के बारे में सही कथन की पहचान करें।
(A) मनोबल एक समूह परिघटना है, व्यक्तिगत नहीं।
(B) मनोबल एक मनोवैज्ञानिक-शारीरिक स्थिति है जो इच्छाशक्ति को प्रभावित करती है।
(C) उच्च वेतन ही उच्च मनोबल का एकमात्र निर्धारक है।
(D) मनोबल एक स्थिर अवधारणा है जो समय के साथ नहीं बदलती है।

45. निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन शामिल हैं, एक को कथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है। सही उत्तर चुनिए।
कथन (A): कर्मचारियों के बीच उच्च मनोबल अक्सर उच्च उत्पादकता से संबंधित होता है।
कारण (R): मनोबल एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है जो सहयोग करने की इच्छा को निर्धारित करती है।
(A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(D) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

46. निम्नलिखित में से कौन कर्मचारी-नियोक्ता संबंधों की औपचारिक पद्धति नहीं है?
(A) संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र (JCM)
(B) ह्विटली परिषदें

NODIA

बदलने का कार्य।
(B) प्राप्तकर्ता द्वारा संदेश की व्याख्या करना।
(C) प्राप्तकर्ता द्वारा प्रेषक को भेजी गई प्रतिपुष्टि।
(D) वह शोर जो संदेश को विकृत करता है।

96. सरकारी सेवा में निम्नलिखित में से कौन अनुशासनात्मक दंड का एक रूप नहीं है?
(A) परिनिंदा (सेंसर)
(B) पदोन्नति
(C) वेतन वृद्धि रोकना
(D) सेवा से बर्खास्तगी

97. एक संगठन कर्मचारियों के अनुभव और कौशल को बढ़ाने के लिए उन्हें विभिन्न कार्यों के माध्यम से स्थानांतरित करता है। इस प्रशिक्षण पद्धति को क्या कहा जाता है?
(A) मामला अध्ययन (केस स्टडी)
(B) कार्य परिवर्तन (जॉब रोटेशन)
(C) व्याख्यान
(D) प्रकोष्ठ प्रशिक्षण

98. भारतीय लोक प्रशासन पर उदारीकरण का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव क्या रहा है?
(A) विकासात्मक/नियंत्रणकारी से नियामक भूमिका की ओर बदलाव।
(B) लाइसेंस-परमिट राज का सुदृढ़ीकरण।
(C) सुशासन के महत्व में गिरावट।
(D) सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की संख्या में वृद्धि।

99. अनुशासनात्मक उपाय के रूप में 'परिनिंदा' (सेंसर) क्या है?
(A) किसी कर्मचारी की सेवा की समाप्ति।
(B) उच्च पद पर पदोन्नति।
(C) कर्मचारी के आचरण की एक औपचारिक और दर्ज की गई अस्वीकृति।
(D) कर्मचारी पर लगाया गया आर्थिक दंड।

100. सूची I को सूची II के साथ सुमेलित करें और सही उत्तर चुनें।
सूची I:
P. लोकपाल
Q. केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC)
R. नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG)
S. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI)
सूची II:
1. सरकारी खातों की लेखापरीक्षा करना
2. निर्दिष्ट आपराधिक मामलों की जांच करना
3. सार्वजनिक पदाधिकारियों के विरुद्ध आरोपों की जांच करना
4. सतर्कता मामलों पर एजेंसियों को सलाह देना
(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-3, Q-4, R-1, S-2
(C) P-2, Q-3, R-4, S-1
(D) P-4, Q-1, R-2, S-3

101. सुशासन के सिद्धांत के रूप में 'विधि के शासन' का अर्थ है:
(A) सरकार द्वारा शक्ति का मनमाना प्रयोग।
(B) कि शासक कानून से ऊपर है।
(C) कानून स्पष्ट, स्थिर और समान रूप से लागू हैं।
(D) कि बिना किसी पूर्व सूचना के कानूनों को प्रतिदिन बदला जा सकता है।

102. निम्नलिखित में से किसे नौकरशाही का एक दुष्कार्य (डिसफंक्शन) माना जाता है?
(A) तार्किकता
(B) लालफीताशाही
(C) पदानुक्रम
(D) निर्वैयक्तिकता

103. भारत में 'संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र' (JCM) की स्थापना किसे बढ़ावा देने के लिए की गई थी?
(A) अंतर-राज्य व्यापार संबंध।
(B) न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच सहयोग।
(C) लोक सेवकों की भर्ती।
(D) सरकार और कर्मचारियों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध।

104. 'सरकार क्या करती है' के बजाय 'सरकार क्या खरीदती है' पर ध्यान केंद्रित करने वाला बजट किसकी विशेषता है?
(A) मद-वार बजट (लाइन-आइटम बजट)
(B) निष्पादन बजट
(C) शून्य-आधारित बजट
(D) कार्यक्रम बजट

105. निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन शामिल हैं, एक को कथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है। सही उत्तर चुनिए।
कथन (A): विकास प्रशासन को एक विशिष्ट नौकरशाही दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है।
कारण (R): यह परिवर्तन-उन्मुखी, लक्ष्य-उन्मुखी और नागरिक-केंद्रित है।
(A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(D) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

106. लोक सेवकों को प्रशिक्षण प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य है:
(A) क्षमताओं और कार्य की आवश्यकताओं के बीच के अंतराल को पाटना।
(B) उनके ज्ञान और कार्य की आवश्यकताओं के बीच के अंतराल को बढ़ाना।
(C) उन्हें लोक सेवा छोड़कर निजी क्षेत्र में जाने के लिए प्रोत्साहित करना।
(D) यह सुनिश्चित करना कि वे अपने प्रारंभिक कौशल तक ही सीमित रहें।

Click Here to Buy book on Amazon

(B) एक नेता के असाधारण गुणों पर।
(C) निर्वैयक्तिक नियमों की प्रणाली पर।
(D) लोकतांत्रिक चुनाव के परिणाम पर।

208. सरकारी विभाग के कार्यों की अंतिम जिम्मेदारी किसके पास होती है?
(A) विभाग के सचिव।
(B) विभाग के प्रभारी मंत्री।
(C) क्षेत्रीय कार्यालय के प्रमुख।
(D) विभाग के कनिष्ठ लिपिक।

209. नेतृत्व के संदर्भ में, 'लेन-देन संबंधी नेता' (ट्रांजैक्शनल लीडर) किस पर ध्यान केंद्रित करते हैं?
(A) अनुयायियों को अभिप्रेरित और प्रोत्साहित करने पर।
(B) नेता और अनुयायी के बीच पुरस्कार आधारित आदान-प्रदान पर।
(C) अहस्तक्षेपकारी दृष्टिकोण पर।
(D) क्रांतिकारी संगठनात्मक परिवर्तन पर।

210. 'विकास योजना' के लिए एक प्रमुख चुनौती किसमें कठिनाई रही है?
(A) पर्याप्त संसाधनों का संग्रहण।
(B) निम्न लक्ष्य निर्धारित करना।
(C) जनता की भागीदारी से बचना।
(D) एक कठोर, ऊपर से नीचे का दृष्टिकोण बनाए रखना।

211. उदारीकरण के प्रभाव के कारण नौकरशाही को और अधिक कैसा होने की आवश्यकता है?
(A) अंतर्मुखी और नियम-बद्ध।
(B) अभिजात वर्गवादी और संरचनात्मक रूप से कठोर।
(C) उद्यमी और नागरिक-केंद्रित।
(D) राज्य के स्वामित्व के विस्तार पर केंद्रित।

212. भारतीय संसद में 'वित्त विधेयक' में क्या होता है?
(A) मंत्रालयों की अनुदान की मांगें।
(B) सरकारी खर्च पर सी.ए.जी. की रिपोर्ट।
(C) संचित निधि से धन निकालने का अधिकार।
(D) कराधान के लिए सरकार के प्रस्ताव।

213. निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें।
कथन I: भ्रष्टाचार सुशासन के सिद्धांतों को कमजोर करता है।
कथन II: यह संसाधनों के असमान वितरण की ओर ले जाता है।
(A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं।
(C) कथन I सत्य है लेकिन कथन II असत्य है।
(D) कथन I असत्य है लेकिन कथन II सत्य है।

214. लोकपाल का अधिकार क्षेत्र किसके अंतर्गत नहीं आता?
(A) कुछ सुरक्षा उपायों के साथ भारत के प्रधानमंत्री।
(B) न्यायपालिका।
(C) संसद सदस्य।
(D) केंद्र सरकार के समूह A, B, C, और D अधिकारी।

215. अभिप्रेरणा तकनीक के रूप में 'कार्य विस्तार' (जॉब एनलार्जमेंट) में शामिल है:
(A) उत्तरदायित्व जोड़कर कार्य की गहराई बढ़ाना।
(B) कर्मचारी को उच्च स्तर के पद पर पदोन्नत करना।
(C) वरिष्ठ अधिकारियों के लिए कार्यों की संख्या कम करना।
(D) समान स्तर की कठिनाई वाले अधिक कार्य जोड़ना।

216. 'नौकरशाही तटस्थता' की अवधारणा का तात्पर्य है कि लोक सेवकों को:
(A) राजनीतिक विचारधारा की परवाह किए बिना सरकार की सेवा करनी चाहिए।
(B) सत्ताधारी दल की विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए।
(C) दलीय राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए।
(D) उन नीतियों में बाधा डालनी चाहिए जिससे वे असहमत हैं।

217. संचार चक्र में 'प्रतिपुष्टि' (फीडबैक) एक महत्वपूर्ण तत्व है क्योंकि यह:
(A) स्वयं मूल संदेश है।
(B) शोर का एक रूप है जो संदेश को विकृत करता है।
(C) प्रेषक को यह जाँचने की अनुमति देता है कि क्या संदेश समझा गया है।
(D) संचार के लिए उपयोग किया जाने वाला माध्यम है।

218. निम्नलिखित में से कौन एक प्रभावी प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य नहीं है?
(A) यह सुनिश्चित करना कि कर्मचारी नवीन कौशल न सीखें।
(B) कर्मचारी की उत्पादकता और दक्षता बढ़ाना।
(C) संगठनात्मक वातावरण और मनोबल में सुधार करना।
(D) उच्च उत्तरदायित्वों के लिए कर्मचारियों को तैयार करना।

219. भर्ती की 'लूट पद्धति' की अक्सर किस कारण आलोचना की जाती है?
(A) सक्षमता और व्यावसायिकता का उच्च स्तर।
(B) सिविल सेवा में राजनीतिक तटस्थता।
(C) एक अत्यधिक अभिप्रेरित और कुशल कार्यबल।
(D) अक्षमता, भ्रष्टाचार और अस्थिरता।

220. सूची I को सूची II के साथ सुमेलित करें और सही उत्तर चुनें।
सूची I:
P. लोकपाल
Q. लोकायुक्त
R. केंद्रीय सतर्कता आयोग
S. प्रशासनिक अधिकरण
सूची II:
1. सरकारी कर्मचारियों के सेवा मामले
2. राज्य स्तर पर भ्रष्टाचार विरोधी निकाय

NODIA

120. कर्मचारी-नियोक्ता संबंधों के संदर्भ में, 'सामूहिक सौदेबाजी' किसे संदर्भित करती है?
(A) एक नियोक्ता और कर्मचारियों के एक समूह के बीच बातचीत।
(B) मजदूरी के संबंध में प्रबंधन का एकपक्षीय निर्णय।
(C) एक व्यक्तिगत कर्मचारी की प्रबंधक से शिकायत।
(D) सरकार द्वारा सभी निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए मजदूरी निर्धारित करना।

121. नौकरशाही की वह विकृति जहाँ नियमों का पालन अपने आप में साध्य बन जाता है, कहलाती है:
(A) भाई-भतीजावाद
(B) भ्रष्टाचार
(C) कर्मकांडवाद (रिचुअलिज्म)
(D) करिश्मा

122. नेतृत्व की परिवर्तनकारी शैली मुख्य रूप से किससे संबंधित है?
(A) अनुयायियों को लक्ष्यों के लिए स्वार्थ से ऊपर उठने के लिए प्रेरित करना।
(B) यथास्थिति बनाए रखना।
(C) पुरस्कार और दंड की प्रणाली।
(D) कर्मचारी के कार्यों की कड़ी निगरानी करना।

123. 'विकास योजना' से 'बाजार आधारित विकास' की ओर बदलाव किसका प्रत्यक्ष प्रभाव है?
(A) गठबंधन की राजनीति का उदय।
(B) पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत।
(C) जनसंख्या में वृद्धि।
(D) उदारीकरण की नीति।

124. बजट केवल एक वित्तीय दस्तावेज नहीं है बल्कि किसका एक साधन भी है?
(A) कार्यकारी कार्यों की न्यायिक समीक्षा।
(B) सार्वजनिक नीति और आर्थिक प्रबंधन।
(C) विदेशी कंपनियों के लिए निजी निवेश।
(D) विशेष रूप से विदेश नीति।

125. आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना देने से मना करने पर पहली अपील किसके पास की जाती है?
(A) भारत के राष्ट्रपति।
(B) केंद्रीय सूचना आयोग।
(C) उसी सार्वजनिक प्राधिकरण में एक वरिष्ठ अधिकारी।
(D) भारत का सर्वोच्च न्यायालय।

126. लोकायुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है?
(A) भारत के प्रधानमंत्री।
(B) सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश।
(C) राज्य के मुख्यमंत्री।
(D) राज्य के राज्यपाल।

127. पदोन्नति प्रणाली के संबंध में गलत कथन की पहचान करें।
(A) पदोन्नति अनुशासनात्मक कार्रवाई का एक रूप है।
(B) यह कर्मचारियों के लिए एक प्रमुख प्रोत्साहन है।
(C) वरिष्ठता का सिद्धांत लागू करना सरल और वस्तुनिष्ठ है।
(D) यदि ठीक से लागू न किया जाए तो योग्यता का सिद्धांत व्यक्तिपरक हो सकता है।

128. 'कार्य-स्थल पर प्रशिक्षण' का क्या लाभ है?
(A) यह अत्यधिक सैद्धांतिक होता है।
(B) यह कर्मचारी को कार्य करते हुए सीखने की अनुमति देता है।
(C) यह प्रशिक्षु को कार्य वातावरण से पूर्णतः अलग कर देता है।
(D) अलग बुनियादी ढांचे की आवश्यकता के कारण यह बहुत महंगा होता है।

NODIA

129. किसने नौकरशाही को दंड-केंद्रित और प्रतिनिधि प्रकारों में द्विभाजित किया?
(A) रॉबर्ट मर्टन
(B) एल्विन गोल्डनर
(C) फिलिप सेल्ज़निक
(D) मिशेल क्रोज़ियर

130. सूची I को सूची II के साथ सुमेलित करें और सही उत्तर चुनें।
सूची I:
P. मद-वार बजट
Q. निष्पादन बजट
R. शून्य-आधारित बजट
S. PPBS
सूची II:
1. प्रतिवर्ष सभी कार्यक्रमों का पुनर्मूल्यांकन
2. नियोजन और बजट का जुड़ाव
3. विशिष्ट वस्तुओं पर व्यय का नियंत्रण
4. भौतिक और वित्तीय पहलुओं का सह-संबंध
(A) P-3, Q-4, R-1, S-2
(B) P-4, Q-3, R-2, S-1
(C) P-3, Q-1, R-4, S-2
(D) P-2, Q-4, R-1, S-3

131. सिविल सेवा की 'राजनीतिक तटस्थता' की अवधारणा को किसके द्वारा चुनौती मिलती है?
(A) नियमित और समय पर पदोन्नति।
(B) आधुनिक प्रबंधन तकनीकों में प्रशिक्षण।
(C) राजनीतिक कारणों से बार-बार और मनमाने स्थानांतरण।
(D) भर्ती के लिए प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं का उपयोग।

132. संचार में 'बाधा' (बैरियर) वह है जो:
(A) समझ को सुगम बनाती है।
(B) स्वयं संदेश है।
(C) संचार का माध्यम है।
(D) प्रभावी संचार को रोकती है या उसमें व्यवधान डालती है।

133. 'जवाबदेही' की अवधारणा किससे निकटता से जुड़ी है?
(A) विवेकाधिकार
(B) गोपनीयता
(C) उत्तरदेयता (आंसरिबिलिटी)
(D) स्वायत्तता

134. ब्रिटेन में स्थापित 'ह्विटली परिषदों' का सबसे उपयुक्त वर्णन कौन सा है?
(A) लोक सेवकों को दंडित करने के लिए एक अनुशासनात्मक निकाय।
(B) विवादों को सुलझाने के लिए प्रतिनिधियों की एक संयुक्त परिषद।
(C) सरकार के लिए एक भर्ती एजेंसी।
(D) वरिष्ठ प्रशासकों के लिए एक प्रशिक्षण संस्थान।

135. निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन शामिल हैं, एक को कथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है। सही उत्तर चुनिए।
कथन (A): वेबर की नौकरशाही का आदर्श प्रारूप एक विश्लेषणात्मक उपकरण है।
कारण (R): यह विधिक-तार्किक संगठन के शुद्ध स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता है।
(A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(D) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

136. 'प्रशिक्षण' और 'शिक्षा' के बीच मौलिक अंतर क्या है?
(A) प्रशिक्षण विशिष्ट और कार्य-उन्मुख है; शिक्षा व्यापक है।
(B) प्रशिक्षण व्यापक और सामान्य है; शिक्षा कार्य-उन्मुख है।
(C) इन दोनों शब्दों के बीच कोई अंतर नहीं है।
(D) प्रशिक्षण वरिष्ठ प्रबंधकों के लिए है; शिक्षा कनिष्ठों के लिए है।

137. निम्नलिखित में से कौन सेवा से 'हटाने' (रिमूवल) के दंड का एक उदाहरण है?
(A) कर्मचारी की अगली वेतन वृद्धि एक वर्ष के लिए रोक दी जाती है।
(B) कर्मचारी को दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर दिया जाता है।
(C) कर्मचारी की सेवा समाप्त कर दी जाती है लेकिन उसे बाद में पुन: नियोजित किया जा सकता है।
(D) कर्मचारी की सेवा समाप्त कर दी जाती है और भविष्य की सेवा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता है।

138. किसी संगठन में कर्मचारियों का मनोबल कम होने की संभावना कब होती है?
(A) जब पदोन्नति पक्षपात और भाई-भतीजावाद पर आधारित हो।
(B) जब नेतृत्व प्रभावी और सहभागी हो।
(C) जब संचार माध्यम खुले और पारदर्शी हों।
(D) जब अच्छे कार्य को लगातार सराहा और पुरस्कृत किया जाए।

139. 'नवीन सार्वजनिक प्रबंधन' (NPM) प्रतिमान निम्नलिखित में से किस पर बल देता है?
(A) पदानुक्रम, नियम और कठोर प्रक्रियात्मक नियमावली।
(B) नौकरशाही परतों की जटिलता बढ़ाना।
(C) पारंपरिक राज्य-स्वामित्व वाले एकाधिकार मॉडल को बनाए रखना।
(D) बाजार तंत्र, दक्षता और निष्पादन माप।

140. वित्तीय प्रशासन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. बजट अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण है।
2. लेखापरीक्षा खातों की कार्योत्तर जांच है।
3. बजट के अधिनियमन में विधायिका की कोई भूमिका नहीं है।
उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) केवल 1 और 3
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 2
(D) 1, 2 और 3

141. 'नौकरशाही विकृति' (ब्यूरो-पैथोलॉजी) शब्द का अर्थ है:
(A) नौकरशाही संगठन के सकारात्मक पहलू।
(B) सरकारी अधिकारियों को मिलने वाले चिकित्सा लाभ।
(C) नौकरशाही के दुष्परिणाम या इसकी कमियां।
(D) नए लोक सेवकों का मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन।

142. एक नेता जो अधीनस्थों से परामर्श करता है और निर्णय लेने में उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करता है, वह प्रदर्शित करता है:
(A) निरंकुश शैली
(B) अहस्तक्षेपकारी शैली
(C) नौकरशाही शैली
(D) लोकतांत्रिक शैली

143. निम्नलिखित में से कौन 'सुशासन' का एक प्रमुख तत्व है?
(A) सर्वसम्मति-उन्मुख निर्णय प्रक्रिया।
(B) सभी शक्तियों का केंद्रीकरण।
(C) कानूनी ढांचे का अभाव।
(D) पारदर्शिता की कमी।

144. आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत सूचना के अनुरोध को अस्वीकार किया जा सकता है यदि वह किसमें सूचीबद्ध छूटों के अंतर्गत आता है?
(A) अधिनियम की प्रस्तावना।
(B) अधिनियम की धारा 8।
(C) सार्वजनिक प्राधिकरण की परिभाषा।
(D) सूचना आयोग का गठन।

Downloaded from www.pdf.tube

145. भारत में भ्रष्टाचार विरोधी निकायों के विकास की निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें:
1. लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम का अधिनियमन।
2. केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) की स्थापना।
3. संथानम समिति का गठन।
4. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की स्थापना।

(A) 4, 3, 2, 1
(B) 3, 4, 2, 1
(C) 4, 2, 3, 1
(D) 3, 2, 4, 1

146. 'पदोन्नति' कर्मचारियों के लिए एक अभिप्रेरक के रूप में कार्य करती है क्योंकि यह उनकी किस आवश्यकता को पूरा करती है?
(A) आत्म-सम्मान, मान्यता और विकास।
(B) सुरक्षा और स्थिरता।
(C) सामाजिक संपर्क।
(D) बुनियादी शारीरिक आवश्यकताएं।

147. निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन शामिल हैं, एक को कथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है। सही उत्तर चुनिए।
कथन (A): मंत्री और लोक सेवक के बीच संबंध मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व पर आधारित होते हैं।
कारण (R): लोक सेवक सीधे संसद के प्रति जवाबदेह होता है।
(A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(D) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

148. 'कार्मिक प्रशासन' की सबसे व्यापक परिभाषा है:
(A) भर्ती, विकास और अभिप्रेरणा से संबंधित गतिविधियाँ।
(B) केवल नए कर्मचारियों को नियुक्त करने की प्रक्रिया।
(C) किसी संगठन के वित्त का प्रबंधन।
(D) संगठन के भीतर अनुशासन लागू करना।

149. मिशेल क्रोज़ियर का नौकरशाही का विश्लेषण निम्नलिखित में से किस पर बल देता है?
(A) वेबर के आदर्श मॉडल की बेजोड़ दक्षता।
(B) सांस्कृतिक संदर्भ और शक्ति संबंधों की भूमिका।
(C) संरचना के भीतर अनौपचारिक समूहों का उन्मूलन।
(D) लिखित नियमों के कड़ाई से पालन की आवश्यकता।

150. भारत जैसे देश में 'विकास योजना' का मुख्य उद्देश्य है:
(A) सामाजिक चिंता के बिना औद्योगिक उत्पादन को अधिकतम करना।
(B) सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक विकास को बढ़ावा देना।
(C) विभिन्न राज्यों के बीच क्षेत्रीय असमानताओं को बढ़ावा देना।
(D) अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका को कम करना।

151. 'औचित्य लेखापरीक्षा' (प्रोपराइटी ऑडिट) किससे संबंधित है?
(A) खातों की गणितीय सटीकता की जाँच करना।
(B) यह सुनिश्चित करना कि व्यय प्रासंगिक नियमों के अनुरूप है।
(C) वित्तीय लेनदेन की वैधता की जांच करना।
(D) व्यय की बुद्धिमत्ता और मितव्ययिता की जांच करना।

NODIA

152. 'क्विड प्रो क्वो' (Quid pro quo) भ्रष्टाचार किसे संदर्भित करता है?
(A) निजी लाभ के बदले सार्वजनिक सेवा का विशिष्ट आदान-प्रदान।
(B) ऐसी स्थिति जहाँ एक सार्वजनिक अधिकारी कर्तव्य की भावना से कार्य करता है।
(C) भ्रष्टाचार जो पूरी प्रणाली में व्याप्त है।
(D) एक सार्वजनिक अधिकारी द्वारा व्यापक जनहित के लिए नियमों में शिथिलता देना।

153. आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत सामान्य मामले में जन सूचना अधिकारी (PIO) के लिए सूचना प्रदान करने की समय सीमा क्या है?
(A) 15 दिन
(B) 45 दिन
(C) 30 दिन
(D) 60 दिन

154. लोकायुक्त के संबंध में गलत कथन की पहचान करें।
(A) लोकायुक्त की शक्तियां सभी राज्यों में समान हैं।
(B) यह राज्य स्तर का भ्रष्टाचार विरोधी ओम्बुड्समैन है।
(C) यह भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करता है।
(D) इसकी सिफारिशें आम तौर पर सलाहकार प्रकृति की होती हैं।

155. भर्ती में 'लूट पद्धति' सबसे प्रसिद्ध रूप से किससे जुड़ी है?
(A) 19वीं शताब्दी के ब्रिटिश सिविल सेवा सुधार।
(B) प्राचीन चीन में प्रयुक्त मंदारिन प्रणाली।
(C) आधुनिक फ्रांसीसी प्रशासनिक संरचना।
(D) 19वीं शताब्दी का संयुक्त राज्य अमेरिका।

156. किसी विशिष्ट कार्य के लिए कौशल और ज्ञान प्रदान करने की प्रक्रिया कहलाती है:
(A) पदोन्नति
(B) प्रशिक्षण
(C) मनोबल
(D) अनुशासन

157. मैक्स वेबर की नौकरशाही की एक प्रमुख आलोचना यह है कि यह पर्याप्त रूप से विचार करने में विफल रही:

107. निम्नलिखित में से कौन 'उर्ध्वमुखी संचार' का एक उदाहरण है?
(A) किसी अधीनस्थ कार्यालय को जारी किया गया सरकारी आदेश।
(B) सभी विभागों को भेजा गया नीतिगत परिपत्र।
(C) मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति।
(D) एक क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत निष्पादन रिपोर्ट।

108. लोक प्रशासन में 'जवाबदेही' शब्द का अर्थ है:
(A) सरकारी कर्मचारियों की संख्या गिनने की क्षमता।
(B) कार्यों और निर्णयों के लिए उत्तर देने का दायित्व।
(C) सरकार के वित्तीय खाते।
(D) किसी अधिकारी की बिना किसी रोक-टोक के कार्य करने की स्वतंत्रता।

109. निम्नलिखित में से कौन कर्मचारी मनोबल मापने की तकनीक नहीं है?
(A) मनोवृत्ति सर्वेक्षण
(B) उत्पादकता रिकॉर्ड का अध्ययन
(C) भर्ती रिकॉर्ड का विश्लेषण
(D) जुर्माना लगाना

110. नौकरशाही के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. मैक्स वेबर ने नौकरशाही को सबसे तार्किक स्वरूप माना।
2. आलोचकों का तर्क है कि नौकरशाही कठोरता से ग्रस्त है।
3. संरक्षण नौकरशाही योग्यता और क्षमता पर आधारित है।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3

111. एफ.एम. मार्क्स द्वारा वर्णित 'अभिभावक नौकरशाही' का सबसे अच्छा उदाहरण है:
(A) चीनी मंदारिन।
(B) 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश सिविल सेवा।
(C) एंड्रयू जैक्सन के अधीन अमेरिकी 'लूट पद्धति'।
(D) आधुनिक फ्रांसीसी सिविल सेवा।

112. पदोन्नति के लिए 'वरिष्ठता-सह-योग्यता' के सिद्धांत का तात्पर्य है कि:
(A) केवल सबसे वरिष्ठ व्यक्ति को ही पदोन्नत किया जाता है।
(B) न्यूनतम वरिष्ठता रखने वालों में योग्यता मुख्य कारक है।
(C) केवल सबसे योग्य व्यक्ति को ही पदोन्नत किया जाता है।
(D) वरिष्ठता मुख्य कारक है, लेकिन योग्यता की अनदेखी की जाती है।

113. वर्तमान समय में मंत्री-लोक सेवक संबंध के पारंपरिक मॉडल के लिए एक प्रमुख चुनौती है:
(A) राजनीतिक रूप से प्रतिबद्ध नौकरशाही की बढ़ती मांग।
(B) स्थायी सिविल सेवा का पूर्ण उन्मूलन।
(C) मंत्रियों से सभी विवेकाधीन शक्तियों को हटाना।
(D) मंत्री की किसी भी राजनीतिक जवाबदेही की कमी।

114. प्रशासन में 'निर्णय-प्रक्रिया' को सबसे अच्छी तरह परिभाषित किया जा सकता है:
(A) विकल्पों में से कार्ययोजना चुनने की प्रक्रिया।
(B) आदेश जारी करने की प्रक्रिया।
(C) अधीनस्थों के पर्यवेक्षण की प्रक्रिया।
(D) वरिष्ठों को रिपोर्ट करने की प्रक्रिया।

115. लोक प्रशासन के लिए उदारीकरण का एक प्रमुख परिणाम किस पर बढ़ा हुआ ध्यान है?
(A) केंद्रीय योजना और राज्य नियंत्रण।
(B) सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार।
(C) शासन और नियामक कार्य।
(D) आयात प्रतिस्थापन नीतियां।

116. भारत के सीएजी (CAG) द्वारा की जाने वाली लेखापरीक्षा मुख्य रूप से है:
(A) भुगतान स्वीकृत करने के लिए पूर्व-लेखापरीक्षा।
(B) लेनदेन के दौरान समवर्ती लेखापरीक्षा।
(C) जनमत जानने के लिए सामाजिक लेखापरीक्षा।
(D) व्यय की वैधता और नियमितता की जाँच के लिए पश्चात लेखापरीक्षा।

117. निम्नलिखित में से कौन भ्रष्टाचार का सामान्य कारण नहीं है?
(A) निर्णय लेने में कम पारदर्शिता।
(B) जटिल और बोझिल प्रक्रियाएं।
(C) मजबूत और प्रभावी जवाबदेही तंत्र।
(D) उच्च विवेकाधीन शक्तियों के साथ कम वेतन।

118. निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें।
कथन I: ओम्बुड्समैन की संस्था एक प्रमुख शिकायत निवारण संस्था है।
कथन II: राष्ट्रीय स्तर पर इसका भारतीय समकक्ष लोकपाल है।
(A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं।
(C) कथन I सत्य है लेकिन कथन II असत्य है।
(D) कथन I असत्य है लेकिन कथन II सत्य है।

119. 'आरोप-पत्र' (चार्ज-शीट) एक औपचारिक दस्तावेज है जो:
(A) किसी कर्मचारी को दी गई पदोन्नति को सूचीबद्ध करता है।
(B) कर्मचारी के वार्षिक प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है।
(C) पूरी हुई जांच के निष्कर्षों का सार प्रस्तुत करता है।
(D) प्रारंभ में कदाचार के विशिष्ट आरोपों का विवरण देता है।

Click Here to Buy book on Amazon

169. निर्णय लेने में नेतृत्व की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है?
(A) निर्णयों को यथासंभव टालना।
(B) उच्चतम व्यक्तिगत लाभ वाले विकल्प को चुनना।
(C) सर्वोत्तम कार्ययोजना चुनने की प्रक्रिया का मार्गदर्शन करना।
(D) बिना किसी प्रश्न के अधीनस्थों द्वारा लिए गए निर्णयों को लागू करना।

170. कर्मचारी-नियोक्ता संबंधों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र का उद्देश्य संघर्ष को बढ़ावा देना है।
2. सामूहिक सौदेबाजी सेवा शर्तों पर बातचीत करने का एक प्रमुख तरीका है।
3. अच्छे संबंधों से उच्च मनोबल और उत्पादकता हो सकती है।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3

171. 'नियोजन, प्रोग्रामिंग, बजटिंग प्रणाली' (PPBS) सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ की गई थी?
(A) यू.के. ट्रेजरी में।
(B) अमेरिकी रक्षा विभाग में।
(C) भारतीय योजना आयोग में।
(D) फ्रांसीसी सिविल सेवा में।

172. 'कुप्रशासन' शब्द, जिसकी जांच ओम्बुड्समैन द्वारा की जाती है, में शामिल है:
(A) केवल भ्रष्टाचार के कार्य।
(B) अक्षमता, विलंब, लापरवाही और प्रशासनिक उदासीनता।
(C) केवल आपराधिक अपराध।
(D) सरकार के केवल नीतिगत निर्णय।

173. लोक सेवकों की 'अनामिकता' किस सिद्धांत का परिणाम है?
(A) न्यायिक पुनरावलोकन
(B) शक्तियों का पृथक्करण
(C) मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व
(D) संघवाद

174. निम्नलिखित में से कौन सीधी भर्ती का प्राथमिक स्रोत है?
(A) पदोन्नति
(B) स्थानांतरण
(C) प्रतिनियुक्ति (डेप्युटेशन)
(D) सभी के लिए खुली प्रतिस्पर्धी परीक्षाएं

175. 'हॉथोर्न प्रयोगों' ने किसके महत्व पर प्रकाश डाला?
(A) कार्यस्थल पर सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारक।
(B) औपचारिक नियम और कानून।
(C) एक सख्त पदानुक्रमित संरचना।
(D) श्रमिकों के आर्थिक उद्देश्य।

176. निम्नलिखित में से कौन संचार के 'माध्यम' (चैनल) का एक उदाहरण है?
(A) प्रेषक का विचार।
(B) एक लिखित ज्ञापन, ईमेल या बातचीत।
(C) प्राप्तकर्ता की व्याख्या।
(D) प्राप्तकर्ता से प्रतिपुष्टि।

177. विकास प्रशासन की चुनौतियाँ इस तथ्य से और बढ़ जाती हैं कि नौकरशाही अक्सर कैसी होती है?
(A) अत्यधिक लचीली और अनुकूलन योग्य।
(B) यथास्थितिवादी और परिवर्तन के प्रति प्रतिरोधी।
(C) परिणामों को शीघ्र प्राप्त करने पर केंद्रित।
(D) नागरिक आवश्यकताओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशील।

178. 'लेखापरीक्षा' किसका एक अनिवार्य घटक है?
(A) वित्तीय जवाबदेही
(B) भर्ती
(C) नीति निर्माण
(D) जनसंपर्क

179. नागरिक का 'जानने का अधिकार' निम्नलिखित में से किसके लिए दार्शनिक आधार है?
(A) सिविल सेवा में पदोन्नति की प्रणाली।
(B) बजट निर्माण की प्रक्रिया।
(C) सूचना का अधिकार अधिनियम।
(D) किसी अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही।

180. भारत में लोकपाल का अधिकार क्षेत्र किस पर है?
(A) केवल कनिष्ठ स्तर के सरकारी अधिकारी।
(B) केवल राज्य सरकारों के कर्मचारी।
(C) केवल न्यायपालिका।
(D) प्रधानमंत्री, मंत्री और संसद सदस्य।

181. एक 'शुष्क' (ड्राई) पदोन्नति, जहाँ एक कर्मचारी को उच्च पदनाम दिया जाता है लेकिन वेतन में वृद्धि नहीं होती, आमतौर पर मानी जाती है:
(A) मनोबल के लिए एक सकारात्मक कारक।
(B) पदोन्नति का सर्वोत्तम रूप।
(C) मनोबल के लिए एक नकारात्मक कारक।
(D) सरकार में पदोन्नति का एकमात्र अनुमत स्वरूप।

182. एफ.एम. मार्क्स के अनुसार 'जातीय नौकरशाही' भर्ती का आधार किसे मानती है?
(A) योग्यता और क्षमता।
(B) विशेषाधिकार प्राप्त जन्म या सामाजिक वर्ग।
(C) खुली प्रतिस्पर्धी परीक्षा।
(D) राजनीतिक संबंध।

NODIA

(A) संगठन की औपचारिक संरचना।
(B) लिखित नियमों और विनियमों का महत्व।
(C) अनौपचारिक सामाजिक गतिशीलता और मानवीय तत्व।
(D) पदानुक्रम का सिद्धांत।

158. एक मंत्री और एक लोक सेवक के बीच आदर्श संबंध कैसा होना चाहिए?
(A) आपसी अविश्वास और संघर्ष का।
(B) लोक सेवक की पूर्ण अधीनता का।
(C) लोक सेवक द्वारा मंत्री को निर्देशित करने का।
(D) आपसी सम्मान, सहयोग और समझ का।

159. एक नेता जो समूह को निर्णय लेने में पूर्ण स्वतंत्रता देता है और स्वयं भाग नहीं लेता है, वह नेतृत्व की किस शैली का उपयोग कर रहा है?
(A) अहस्तक्षेपकारी (लेसफेयर)
(B) निरंकुश
(C) लोकतांत्रिक
(D) पितृसत्तात्मक

160. सूची I को सूची II के साथ सुमेलित करें और सही उत्तर चुनें।
सूची I:
P. जवाबदेही
Q. पारदर्शिता
R. विधि का शासन
S. भागीदारी
सूची II:
1. निर्णय और कार्यान्वयन सार्वजनिक जांच के लिए उपलब्ध हैं।
2. कानूनी ढांचा निष्पक्ष है और समान रूप से लागू है।
3. निर्णय लेने में नागरिकों की आवाज होती है।
4. अधिकारी अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी होते हैं।
(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-4, Q-3, R-1, S-2
(C) P-4, Q-1, R-2, S-3
(D) P-2, Q-4, R-3, S-1

161. संचार में 'शब्दार्थ संबंधी बाधाएं' (सिमेंटिक बैरियर) किससे उत्पन्न होती हैं?
(A) संगठन की पदानुक्रमित संरचना।
(B) शब्दों और प्रतीकों के अर्थ से जुड़ी समस्याएं।
(C) प्रेषक या प्राप्तकर्ता की भावनात्मक स्थिति।
(D) प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच शारीरिक दूरी।

162. उदारीकरण के बाद के युग में भारतीय नौकरशाही के लिए मुख्य चुनौतियों में से एक है:
(A) आर्थिक गतिविधि के सुगमकर्ता के रूप में एक नई भूमिका के अनुकूल होना।
(B) राज्य के एकाधिकार को पुनः स्थापित करना।
(C) तकनीकी अपनाने के सभी रूपों का विरोध करना।
(D) व्यवसायों के लिए प्रक्रियात्मक बाधाओं में वृद्धि करना।

163. बजटीय प्रक्रिया में प्रथम चरण है:
(A) विधायिका द्वारा अधिनियमन।
(B) बजट का निष्पादन।
(C) कार्यपालिका द्वारा अनुमानों की तैयारी और निरूपण।
(D) खातों की लेखापरीक्षा।

164. भ्रष्टाचार से लड़ने की रणनीति के रूप में 'निवारक सतर्कता' किस पर ध्यान केंद्रित करती है?
(A) कृत्य के पश्चात भ्रष्ट अधिकारियों को दंडित करना।
(B) भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करना।
(C) केवल छापेमारी और तलाशी अभियान चलाना।
(D) भ्रष्टाचार के अवसरों को कम करने के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाना।

165. निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन शामिल हैं, एक को कथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है। सही उत्तर चुनिए।
कथन (A): लोकपाल की संस्था स्वतंत्र होने के लिए अभिप्रेत है।
कारण (R): इसे बिना किसी भय के उच्च पदस्थ अधिकारियों की जांच करनी चाहिए।
(A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(D) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

166. एक सरकारी विभाग सबसे वरिष्ठ लिपिक को पदोन्नत करने का निर्णय लेता है, भले ही किसी कनिष्ठ का प्रदर्शन बेहतर हो। यह किस पर आधारित है?
(A) योग्यता का सिद्धांत
(B) वरिष्ठता का सिद्धांत
(C) लूट पद्धति
(D) संरक्षण का सिद्धांत

167. निम्नलिखित में से कौन अनुशासनात्मक कार्रवाई का उद्देश्य नहीं है?
(A) अपराधी में सुधार करना।
(B) दूसरों को इसी तरह के कार्यों से रोकना।
(C) संगठनात्मक मानकों को बनाए रखना।
(D) कर्मचारियों को उत्पीड़ित करना।

168. वेबर की नौकरशाही में 'निर्वैयक्तिकता' के गुण का अर्थ है कि:
(A) नियम बिना किसी व्यक्तिगत पक्षपात के लागू होने चाहिए।
(B) अधिकारियों को अमित्र होना चाहिए।
(C) संगठन का कोई पृथक व्यक्तित्व नहीं होता।
(D) भर्ती व्यक्तिगत संबंधों पर आधारित होती है।

Downloaded from www.pdf.tube

का दुरुपयोग कर सकते हैं।
(A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(D) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

196. भारत में केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी?
(A) गोरवाला समिति
(B) एप्पलबी रिपोर्ट
(C) प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग
(D) संथानम समिति

197. 'व्हिसलब्लोइंग' (Whistleblowing) किसका कार्य है?
(A) सार्वजनिक रूप से प्रबंधन की प्रशंसा करना।
(B) कार्यालय की गतिविधियों में भाग लेना।
(C) गलत कार्य या भ्रष्टाचार को उजागर करना।
(D) उच्च वेतन की मांग करना।

198. लोक सेवा आयोग का प्राथमिक उद्देश्य है:
(A) सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण आयोजित करना।
(B) लोक सेवाओं के लिए भर्ती करना और कार्मिक मामलों पर सलाह देना।
(C) सरकारी खातों की लेखापरीक्षा करना।
(D) सरकारी नीति तैयार करना।

199. विकास योजनाओं की विफलता का एक प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सा है?
(A) एक अत्यधिक कुशल और लचीली नौकरशाही।
(B) अत्यधिक सार्वजनिक भागीदारी।
(C) महत्वाकांक्षी लक्ष्यों का अभाव।
(D) नीति निर्माण और कार्यान्वयन के बीच एक बड़ा अंतराल।

200. नौकरशाही-विकास संबंधों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. एक कठोर, नियम-बद्ध नौकरशाही विकास के लिए उपयुक्त है।
2. विकास प्रशासन के लिए एक लचीली नौकरशाही की आवश्यकता होती है।
3. भ्रष्टाचार विकास के प्रयासों को गंभीर रूप से कमजोर कर सकता है।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 1 और 3
(C) केवल 2 और 3
(D) 1, 2 और 3

201. लेखापरीक्षा में 'वैधता का सिद्धांत' का अर्थ है यह जाँचना कि:
(A) व्यय बुद्धिमानी भरा है।
(B) व्यय मितव्ययी है।
(C) व्यय कानून और नियमों के अनुरुप है।
(D) व्यय ने वांछित परिणाम प्राप्त किया है।

202. 'ओम्बुड्समैन' की अवधारणा नागरिक को किससे बचाने के लिए निर्मित है?
(A) कार्यपालिका द्वारा अन्याय और कुप्रशासन।
(B) विदेशी आक्रमण।
(C) न्यायपालिका के निर्णय।
(D) विधायिका द्वारा पारित कानून।

203. 'लालफीताशाही' (Red Tape) शब्द का प्रयोग अक्सर नौकरशाही की किसलिए आलोचना करने हेतु किया जाता है?
(A) दक्षता और गति।
(B) पारदर्शिता का उच्च स्तर।
(C) अभिनव दृष्टिकोण।
(D) औपचारिक नियमों का अत्यधिक पालन जिससे विलंब होता है।

204. उच्च मनोबल के निर्माण और अनुरक्षण का एक प्रमुख घटक निम्नलिखित में से कौन सा है?
(A) एक निरंकुश और गुप्त नेतृत्व शैली।
(B) साझा उद्देश्य और स्पष्ट संचार।
(C) असंगत अनुशासनात्मक अभ्यास।
(D) विकास के सीमित अवसर।

205. भर्ती प्रक्रिया के निम्नलिखित चरणों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करें:
1. उम्मीदवारों को आकर्षित करना।
2. रिक्तियों का निर्धारण।
3. उपयुक्त उम्मीदवारों का चयन।
4. चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति।
(A) 1, 2, 3, 4
(B) 2, 1, 3, 4
(C) 2, 3, 1, 4
(D) 1, 3, 2, 4

206. सेवा से 'बर्खास्तगी' (डिस्मिसल) 'हटाने' (रिमूवल) की तुलना में अधिक गंभीर है क्योंकि:
(A) हटाने से पुन: नियोजन की अनुमति मिलती है; बर्खास्तगी से नहीं।
(B) बर्खास्तगी अस्थायी है, जबकि हटाना स्थायी है।
(C) बर्खास्तगी पेंशन के साथ होती है, जबकि हटाना नहीं।
(D) बर्खास्तगी भविष्य के सरकारी नियोजन के लिए अयोग्य घोषित कर देती है।

207. वेबर के अनुसार, पारंपरिक सत्ता की वैधता किस पर आधारित है?
(A) स्थापित रीति-रिवाजों और प्राचीन परंपराओं पर।

NODIA

183. निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें।
कथन I: मंत्री विभाग का राजनीतिक प्रमुख होता है।
कथन II: लोक सेवक विभाग का प्रशासनिक प्रमुख होता है।
(A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं।
(C) कथन I सत्य है लेकिन कथन II असत्य है।
(D) कथन I असत्य है लेकिन कथन II सत्य है।

184. 'अहस्तक्षेपकारी' नेतृत्व शैली तब सबसे प्रभावी होती है जब अनुयायी कैसे हों?
(A) अत्यधिक कुशल, अभिप्रेरित और स्वतंत्र रूप से कार्य करने में सक्षम।
(B) अकुशल और अनुत्साहित।
(C) तत्काल दिशा-निर्देश की आवश्यकता वाली संकट की स्थिति में।
(D) संगठन में नए और जिन्हें कड़ी निगरानी की आवश्यकता हो।

185. उदारीकरण के बाद के युग में 'सार्वजनिक-निजी भागीदारी' (PPP) का बढ़ता महत्व दर्शाता है:
(A) सेवा प्रावधान से राज्य की पूर्ण वापसी।
(B) सभी निजी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण।
(C) सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने के लिए एक सहयोगात्मक प्रयास।
(D) पूरी तरह से राज्य-नियंत्रित अर्थव्यवस्था की ओर वापसी।

186. बजट पर विधायी नियंत्रण किसके माध्यम से किया जाता है?
(A) चर्चा, अनुदानों पर मतदान और विनियोग विधेयकों को पारित करना।
(B) न्यायपालिका का हस्तक्षेप।
(C) सी.ए.जी. की लेखापरीक्षा रिपोर्ट।
(D) कार्यपालिका की व्यय करने की स्वैच्छिक शक्ति।

187. संथानम समिति की नियुक्ति किसकी समस्या का अध्ययन करने के लिए की गई थी?
(A) केंद्र-राज्य संबंध।
(B) चुनावी सुधार।
(C) पंचायती राज संस्थाएं।
(D) प्रशासन में भ्रष्टाचार।

188. निम्नलिखित में से कौन 'कुप्रशासन' का एक उदाहरण है?
(A) एक सरकारी कार्यालय द्वारा त्वरित सेवा प्रदान करना।
(B) लापरवाही के कारण किसी अधिकारी द्वारा फाइल खो देना।
(C) करों को बढ़ाने का नीतिगत निर्णय।
(D) योग्यता के आधार पर पदोन्नति पाने वाला कर्मचारी।

189. प्रशिक्षण की 'सैंडविच पद्धति' किसका एक प्रकार है?
(A) कार्य-स्थल पर प्रशिक्षण।
(B) कार्य-बाह्य प्रशिक्षण।
(C) दोनों तत्वों को मिलाने वाला एक संकर मॉडल।
(D) अनौपचारिक प्रशिक्षण।

190. सूची I को सूची II के साथ सुमेलित करें और सही उत्तर चुनें।
सूची I:
P. भर्ती
Q. प्रशिक्षण
R. निष्पादन मूल्यांकन
S. शिकायत निवारण
सूची II:
1. वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (ACR)
2. संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र (JCM)
3. लिखित परीक्षा और साक्षात्कार
4. मामला अध्ययन विधि
(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-3, Q-4, R-1, S-2
(C) P-2, Q-3, R-4, S-1
(D) P-4, Q-1, R-2, S-3

191. अनुशासनात्मक जांच लंबित रहने तक 'निलंबन' क्या है?
(A) निष्पक्ष जांच के लिए कर्तव्यों से अस्थायी रूप से हटाया जाना।
(B) एक अंतिम दंड।
(C) एक पदोन्नति।
(D) अच्छी सेवा के लिए एक पुरस्कार।

192. आलोचकों के अनुसार, नौकरशाही की पदानुक्रमित संरचना मुख्य रूप से किसे बाधित करती है?
(A) अधोमुखी संचार।
(B) उर्ध्वमुखी और क्षैतिज संचार।
(C) औपचारिक संचार।
(D) लिखित संचार।

193. 'विकास प्रशासन' में 'विकास' की अवधारणा का तात्पर्य है:
(A) केवल आर्थिक वृद्धि।
(B) सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन।
(C) कानून व्यवस्था बनाए रखना।
(D) यथास्थिति बनाए रखना।

194. विधायिका द्वारा पारित 'विनियोग अधिनियम':
(A) संचित निधि से धन निकालने के लिए अधिकृत करता है।
(B) सरकार को कर एकत्र करने के लिए अधिकृत करता है।
(C) सी.ए.जी. की वार्षिक रिपोर्ट है।
(D) संसद में राष्ट्रपति का भाषण है।

195. निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन शामिल हैं, एक को कथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है। सही उत्तर चुनिए।
कथन (A): सुशासन के लिए सुदृढ़ जवाबदेही तंत्र की आवश्यकता होती है।
कारण (R): जवाबदेही के बिना, सार्वजनिक अधिकारी शक्ति

Click Here to Buy book on Amazon

3. संघ स्तर पर भ्रष्टाचार विरोधी निकाय
4. सरकार के भीतर सतर्कता मामलों का पर्यवेक्षण

(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-3, Q-2, R-4, S-1
(C) P-2, Q-3, R-1, S-4
(D) P-3, Q-4, R-2, S-1

221. पदोन्नति में 'योग्यता सिद्धांत' को लागू करने में एक प्रमुख समस्या है:
(A) इसके अनुप्रयोग की सुगमता।
(B) वरिष्ठ कर्मचारियों का पक्ष लेने की प्रवृत्ति।
(C) योग्यता को वस्तुनिष्ठ रूप से मापने में कठिनाई।
(D) इसके सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत मानदंड।

222. मैक्स वेबर द्वारा प्रयुक्त 'नौकरशाही' शब्द किसे संदर्भित करता है?
(A) अक्षम और हस्तक्षेपकारी अधिकारियों द्वारा शासन।
(B) एक सम्राट द्वारा व्यक्तिगत शासन की प्रणाली।
(C) कोई भी बड़े पैमाने का संगठन, चाहे वह सार्वजनिक हो या निजी।
(D) विधिक-तार्किक सत्ता पर आधारित एक सामाजिक संगठन।

223. विकास प्रशासन की सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है?
(A) सुदृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति और प्रशासनिक प्रतिबद्धता।
(B) एक कठोर और अनम्य प्रशासनिक संरचना।
(C) सार्वजनिक भागीदारी की पूर्ण अनुपस्थिति।
(D) यथास्थिति बनाए रखने पर ध्यान।

224. 'कटौती प्रस्ताव' (कट मोशन) विधायिका द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक उपकरण है जिसका उद्देश्य है:
(A) अनुदान की राशि बढ़ाना।
(B) सरकारी नीति के प्रति असहमति व्यक्त करना।
(C) बिना किसी चर्चा के बजट को मंजूरी देना।
(D) वित्त मंत्री को बधाई देना।

225. निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन शामिल हैं, एक को कथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है। सही उत्तर चुनिए।
कथन (A): संचार किसी संगठन का जीवन रक्त है।
कारण (R): कोई भी संगठन सूचना प्रवाह के बिना कार्य नहीं कर सकता।
(A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(D) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

226. 'सामाजिक लेखापरीक्षा' (सोशल ऑडिट) पारंपरिक वित्तीय लेखापरीक्षा से किस प्रकार भिन्न है?
(A) यह सामाजिक-नैतिक निष्पादन और सामुदायिक प्रभाव पर केंद्रित है।
(B) यह केवल संगठन के वित्तीय खातों पर ध्यान केंद्रित करती है।
(C) यह केवल कानूनी नियमों के अनुपालन पर ध्यान केंद्रित करती है।
(D) यह उत्पादन प्रक्रिया की दक्षता पर ध्यान केंद्रित करती है।

227. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 ने किस पूर्ववर्ती कानून का स्थान लिया?
(A) आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923
(B) सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम, 2002
(C) सूचना सुरक्षा प्रोटोकॉल अधिनियम, 2001
(D) इस विषय पर कोई पूर्व कानून मौजूद नहीं था।

228. "स्थायी किंतु राजनीतिक रूप से तटस्थ" की अवधारणा किसकी आदर्श भूमिका का सर्वोत्तम वर्णन करती है?
(A) मंत्री
(B) संसद सदस्य
(C) राजनीतिक दल का कार्यकर्ता
(D) लोक सेवक

229. इनमें से कौन 'कार्य-बाह्य' (ऑफ-द-जॉब) प्रशिक्षण की एक विधि है?
(A) कोचिंग
(B) कार्य परिवर्तन
(C) मामला अध्ययन
(D) प्रशिक्षुता

230. पदोन्नति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. यह किसी कर्मचारी की अधोमुखी गति है।
2. इसमें उच्च वेतन, प्रतिष्ठा और उत्तरदायित्व शामिल हैं।
3. पदोन्नति के मुख्य सिद्धांत वरिष्ठता और योग्यता हैं।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 1 और 3
(C) केवल 2 और 3
(D) 1, 2 और 3

231. निम्नलिखित में से कौन किसी संगठन में नेता की भूमिका का सर्वोत्तम वर्णन करता है?
(A) पूर्णतः अपने स्वयं के कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना।
(B) लचीलेपन के बिना नियमों को कड़ाई से लागू करना।
(C) एक निष्क्रिय पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करना।
(D) एक समूह को लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रभावित और अभिप्रेरित करना।

Downloaded from www.pdf.tube

232. सामान्य अर्थों में 'नौकरशाही' शब्द का अक्सर नकारात्मक अर्थ लिया जाता है, जिसका तात्पर्य है:
(A) अक्षमता और लालफीताशाही
(B) दक्षता और गति
(C) तटस्थता और निष्पक्षता
(D) नवाचार और लचीलापन

233. विकास की आवश्यकताओं के अनुरूप स्वयं को ढालने में नौकरशाही की विफलता का मुख्य कारण माना जाता है:
(A) इसकी लक्ष्य-उन्मुख प्रकृति।
(B) इसका नागरिक-अनुकूल दृष्टिकोण।
(C) इसकी प्रक्रियात्मक कठोरता और अभिजात दृष्टिकोण।
(D) सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रेरणा का उच्च स्तर।

234. व्यावसायिक संदर्भ में शून्य-आधारित बजटिंग (ZBB) दृष्टिकोण सर्वप्रथम किसके द्वारा लागू किया गया था?
(A) पीटर ए. पीर
(B) पीटर ड्रकर
(C) रॉबर्ट मैकनामरा
(D) आरोन विल्डावस्की

235. 'सुशासन' (गुड गवर्नेंस) की अवधारणा किस पर बल देती है?
(A) नीतियों के केवल आर्थिक परिणामों पर।
(B) नौकरशाही नियंत्रण को सुदृढ़ करने पर।
(C) नागरिक भागीदारी को कम करने पर।
(D) निर्णय लेने और कार्यान्वयन की प्रक्रिया पर।

236. द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने "शासन में नैतिकता" पर अपनी रिपोर्ट में किसकी स्थापना की सिफारिश की थी?
(A) नीति आयोग
(B) लोकपाल
(C) राष्ट्रीय विकास परिषद
(D) नवीन अखिल भारतीय सेवा

237. प्रशासन में भ्रष्टाचार का एक प्रमुख कारण क्या है?
(A) पारदर्शिता और जवाबदेही का उच्च स्तर।
(B) न्यूनतम विवेकाधिकार के साथ सरल प्रक्रियाएं।
(C) उच्च विवेकाधिकार और कम जवाबदेही के साथ सत्ता का एकाधिकार।
(D) एक सुदृढ़ नैतिक ढांचा और आचार संहिता।

238. निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें।
कथन I: उच्च मनोबल सदैव उच्च उत्पादकता की सुनिश्चितता देता है।
कथन II: मनोबल कार्य करने की इच्छा उत्पन्न करता है, किंतु उत्पादकता अन्य कारकों पर भी निर्भर है।
(A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं।
(C) कथन I असत्य है लेकिन कथन II सत्य है।
(D) कथन I सत्य है लेकिन कथन II असत्य है।

239. 'पद वर्गीकरण' एक ऐसी प्रणाली है जो किसका मूल्यांकन करती है?
(A) स्वयं कार्य के कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का।
(B) उस पद पर कार्यरत व्यक्ति का।
(C) कर्मचारी की वरिष्ठता का।
(D) कर्मचारी के निष्पादन का।

240. एक मंत्री और एक लोक सेवक के बीच आदर्श संबंध के लिए मंत्री को क्या प्रदान करना चाहिए?
(A) विस्तृत प्रशासनिक निर्देश।
(B) नीतिगत मार्गदर्शन और राजनीतिक दिशा।
(C) कार्यालय के कार्य का दैनिक पर्यवेक्षण।
(D) अधिकारियों को अनुचित संरक्षण।

241. सुशासन के संदर्भ में 'जवाबदेही' मुख्य रूप से क्या सुनिश्चित करती है?
(A) कि अधिकारी पूर्णतः दण्डमुक्ति के साथ कार्य कर सकें।
(B) कि सार्वजनिक अधिकारी अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी हों।
(C) कि नागरिकों के पास त्रुटियों के विरुद्ध कोई उपचार न हो।
(D) कि सरकार की समस्त सूचनाएं गुप्त रखी जाएं।

242. 'ब्रेनस्टॉर्मिंग' (वैचारिक मंथन) एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग प्रशिक्षण में किसे बढ़ावा देने के लिए किया जाता है?
(A) रचनात्मक सोच और समस्या-समाधान
(B) रटकर सीखना
(C) शारीरिक कौशल
(D) नियमों का अंधानुकरण

243. भारतीय नौकरशाही पर उदारीकरण के प्रभाव ने कौशल में किस बदलाव को आवश्यक बना दिया है?
(A) आई.टी. साक्षरता से मैन्युअल अभिलेखन की ओर।
(B) घरेलू फोकस से वैश्विक प्रवृत्तियों की उपेक्षा की ओर।
(C) नियमन से अनुबंध प्रबंधन और वार्ता की ओर।
(D) सुगमता प्रदान करने से आदेश और नियंत्रण की ओर।

244. संसद द्वारा पारित 'लेखानुदान' (Vote on Account) सरकार को क्या करने में सक्षम बनाता है?
(A) पूर्ण बजट प्रस्तुत करना।
(B) तुरंत नए कर अधिरोपित करना।
(C) आर्थिक सर्वेक्षण पर चर्चा करना।
(D) वित्तीय वर्ष के एक भाग के लिए व्यय हेतु धन निकालना।

245. लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों के चयन के लिए बनी समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है?
(A) भारत के राष्ट्रपति
(B) भारत के मुख्य न्यायाधीश
(C) भारत के प्रधानमंत्री
(D) भारत के गृह मंत्री

NODIA

246. सिविल सेवा में 'क्षैतिज गतिशीलता' (हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी) किसे संदर्भित करती है?
(A) उच्च पद पर पदोन्नति।
(B) उसी स्तर पर दूसरे पद पर स्थानांतरण।
(C) निचले पद पर पदावनति।
(D) सेवा से सेवानिवृत्ति।

247. 'पीटर सिद्धांत' क्या सुझाव देता है?
(A) केवल सर्वाधिक सक्षम लोग ही शीर्ष पर पहुँचते हैं।
(B) पदोन्नति प्रणालियाँ सदैव कुशल होती हैं।
(C) वरिष्ठता पदोन्नति के लिए सर्वोत्तम सिद्धांत है।
(D) लोगों को तब तक पदोन्नत किया जाता है जब तक वे अपनी अक्षमता के स्तर तक नहीं पहुँच जाते।

248. निर्णय लेने का 'तार्किक' (रेशनल) मॉडल यह मानता है कि निर्णय लेने वाला:
(A) पूर्ण सूचना रखता है और सभी विकल्पों का मूल्यांकन करता है।
(B) भावना और अंतर्ज्ञान के आधार पर निर्णय लेता है।
(C) निर्णय लेने से पूर्णतः बचता है।
(D) उपलब्ध प्रथम संतोषजनक विकल्प को चुनता है।

249. निम्नलिखित में से कौन मैक्स वेबर की 'आदर्श प्रारूप' नौकरशाही की विशेषता नहीं है?
(A) श्रम का विभाजन
(B) एक सुपरिभाषित पदानुक्रम
(C) तदर्थ और मनमाने नियमों की प्रणाली
(D) नियमों का निर्वैयक्तिक अनुप्रयोग

250. सूची I को सूची II के साथ सुमेलित करें और सही उत्तर चुनें।
सूची I:
P. विशेषक (ट्रेट) सिद्धांत
Q. व्यवहारवादी सिद्धांत
R. स्थितिजन्य सिद्धांत
S. परिवर्तनकारी सिद्धांत
सूची II:
1. संदर्भ और अनुयायियों की परिपक्वता पर ध्यान केंद्रित करता है।
2. नेता क्या करते हैं (कार्य बनाम संबंध) इस पर ध्यान केंद्रित करता है।
3. अनुयायियों को प्रेरित और ऊपर उठाने पर ध्यान केंद्रित करता है।
4. नेता के व्यक्तिगत गुणों पर ध्यान केंद्रित करता है।
(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-4, Q-3, R-2, S-1
(C) P-2, Q-1, R-4, S-3
(D) P-4, Q-2, R-1, S-3

251. ह्विटली परिषदों जैसे तंत्रों का प्राथमिक उद्देश्य है:
(A) कर्मचारियों की स्थिति को कमजोर करना।
(B) प्रबंधकीय विशेषाधिकार बढ़ाना।
(C) एक भर्ती निकाय के रूप में कार्य करना।
(D) सहयोग और समाधान के लिए एक मंच प्रदान करना।

252. 'बजट' शब्द फ्रांसीसी शब्द 'बोउगेट' (bougette) से लिया गया है, जिसका अर्थ है:
(A) एक वित्तीय विवरण
(B) चमड़े का थैला या बटुआ
(C) अनुमान लगाना
(D) कानून का एक अधिनियम

253. पारदर्शिता और जवाबदेही के संबंध में सही कथन की पहचान करें।
(A) वे लोक प्रशासन में परस्पर विरोधी अवधारणाएं हैं।
(B) पारदर्शिता जवाबदेही के लिए एक अनिवार्य शर्त है।
(C) जवाबदेही नौकरशाही गोपनीयता बढ़ाकर प्राप्त की जाती है।
(D) ये अवधारणाएं केवल निजी कंपनियों के लिए प्रासंगिक हैं।

254. लोकायुक्त की संस्था किस स्तर पर शिकायत निवारण तंत्र का एक उदाहरण है?
(A) केंद्रीय स्तर
(B) नगरपालिका स्तर
(C) अंतरराष्ट्रीय स्तर
(D) राज्य स्तर

255. निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन शामिल हैं, एक को कथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है। सही उत्तर चुनिए।
कथन (A): वरिष्ठता के सिद्धांत को प्रशासित करना सरल है।
कारण (R): यह सेवा की अवधि पर आधारित है, जो कि वस्तुनिष्ठ है।
(A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(D) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

256. उच्च स्तरों पर 'सीधी भर्ती' की एक प्रमुख आलोचना यह है कि यह:
(A) नवीन प्रतिभा और विचार ला सकती है।
(B) वर्तमान कर्मचारियों के मनोबल को प्रभावित कर सकती है।
(C) उम्मीदवारों के समूह को व्यापक बना सकती है।
(D) अंतर्प्रजनन (इन-ब्रीडिंग) की ओर ले जा सकती है।

257. 'हेलो प्रभाव' (Halo Effect) किसमें होने वाली एक संभावित त्रुटि है?
(A) बजटिंग
(B) निष्पादन मूल्यांकन (परफॉर्मेंस अप्रेजल)
(C) लेखापरीक्षा (ऑडिट)

Click Here to Buy book on Amazon

उत्तर (व्याख्या सहित)

1. (B) संगठनात्मक रिक्तियों के लिए आवेदकों की खोज करने की प्रक्रिया।
कार्मिक प्रशासन में भर्ती एक सकारात्मक प्रक्रिया है जिसका मुख्य उद्देश्य संगठन के रिक्त पदों के लिए योग्य प्रत्याशियों को आकर्षित करना और उन्हें आवेदन हेतु प्रेरित करना है। यह चयन प्रक्रिया का प्राथमिक चरण है, जहाँ संभावित कर्मियों का एक विस्तृत समूह तैयार किया जाता है। इसके माध्यम से ही कुशल मानव संसाधन की पहचान संभव होती है, जिससे संगठन की कार्यक्षमता और लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित की जाती है।

2. (C) कथन I सत्य है लेकिन कथन II असत्य है।
प्रशिक्षण की कार्य-बाह्य विधियों के अंतर्गत कर्मचारियों को उनके नियमित कार्य स्थल और सामान्य वातावरण से अलग प्रशिक्षण दिया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य उन्हें बिना किसी दबाव के नवीन तकनीक सीखने का अवसर प्रदान करना है। प्रकोष्ठ प्रशिक्षण भी कार्य स्थल से दूर एक कृत्रिम कार्य परिवेश तैयार करके दिया जाता है, न कि प्रत्यक्ष कार्य स्थल पर। अतः, इसे कार्य-पर पद्धति नहीं माना जाता, बल्कि यह कार्य-बाह्य प्रशिक्षण का हिस्सा है।

3. (C) संरक्षण का सिद्धांत
सार्वजनिक क्षेत्र में पदोन्नति मुख्य रूप से योग्यता और वरिष्ठता के सिद्धांतों पर आधारित होती है, जो प्रशासनिक निष्पक्षता सुनिश्चित करते हैं। योग्यता का सिद्धांत श्रेष्ठ प्रदर्शन को पुरस्कृत करता है, जबकि वरिष्ठता का सिद्धांत सेवा की लंबी अवधि को महत्व देता है। इसके विपरीत, संरक्षण का सिद्धांत पक्षपात और राजनीतिक हस्तक्षेप को बढ़ावा देता है, जो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था हेतु सर्वथा अनुपयुक्त है। यह प्रशासनिक शुचिता को नष्ट करता है, इसलिए इसे पदोन्नति का वैध सिद्धांत नहीं माना जाता।

4. (D) कार्य और समूह से प्राप्त होने वाली कुल संतुष्टि।
संगठन में मनोबल एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है जो कर्मचारियों के मानसिक दृष्टिकोण और कार्य के प्रति उनके उत्साह को दर्शाती है। यह केवल व्यक्तिगत संतुष्टि तक सीमित नहीं है, बल्कि समूह के भीतर एकता और सामान्य लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्धता को भी समाहित करती है। उच्च मनोबल से कार्यक्षमता और सहयोग में वृद्धि होती है, जबकि निम्न मनोबल उत्पादकता में बाधा उत्पन्न करता है। यह कर्मचारियों के विश्वास और संगठनात्मक उद्देश्यों में सामंजस्य का महत्वपूर्ण सूचक है।

5. (C) यह तार्किकता और निर्वैयक्तिकता द्वारा परिभाषित एक संरचना है।
मैक्स वेबर द्वारा प्रतिपादित नौकरशाही का सिद्धांत एक आदर्श और विधिक-तार्किक प्रारूप प्रस्तुत करता है। इस प्रणाली में समस्त प्रशासनिक कार्य पूर्व-निर्धारित लिखित नियमों और विधिक प्रक्रियाओं के अनुसार संचालित किए जाते हैं। यहाँ निर्वैयक्तिकता का अर्थ है कि निर्णय व्यक्तिगत भावनाओं या पक्षपात के बजाय केवल योग्यता और नियमों के आधार पर लिए जाते हैं। यह ढांचा पदानुक्रमित संरचना और श्रम विभाजन पर आधारित है, जो आधुनिक संगठनों की कुशलता हेतु अनिवार्य और तार्किक माना गया है।

6. (B) विशिष्ट क्षेत्रों के उम्मीदवारों तक ही आवेदनों को सीमित करना।
भर्ती के संदर्भ में नकारात्मक भर्ती उस प्रक्रिया को कहा जाता है जहाँ चयन के दायरे को कृत्रिम रूप से संकुचित किया जाता है। जब आवेदनों को केवल कुछ विशिष्ट क्षेत्रों या समूहों तक ही सीमित कर दिया जाता है, तो यह योग्य उम्मीदवारों के एक व्यापक वर्ग को अवसर से वंचित कर देता है। यह पद्धति प्रतिभा की खोज के बजाय योग्य लोगों को बाहर करने की प्रवृत्ति को दर्शाती है। इसके विपरीत, विज्ञापन और रोजगार कार्यालयों का उपयोग करना सकारात्मक भर्ती है।

7. (D) समस्या को परिभाषित करना और नीति के लिए उद्देश्य निर्धारित करना।
किसी भी नीति निर्माण प्रक्रिया के प्रारंभिक चरण में नेतृत्व का सबसे महत्वपूर्ण कार्य समस्या की सटीक पहचान करना और स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना होता है। शहरी अपशिष्ट प्रबंधन जैसी जटिल समस्याओं के समाधान हेतु सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि मुख्य चुनौतियाँ क्या हैं। जब तक उद्देश्य स्पष्ट नहीं होंगे, तब तक संसाधनों का प्रभावी आवंटन और क्रियान्वयन संभव नहीं है। नेतृत्व की यह दूरदर्शिता ही भविष्य की कार्ययोजना को सही दिशा और सफलता प्रदान करती है।

8. (A) नीति निर्माण में लोक सेवक के पास अंतिम अधिकार होता है।
संसदीय लोकतंत्र में नीति निर्माण का अंतिम उत्तरदायित्व और अधिकार निर्वाचित मंत्री के पास होता है, क्योंकि वे जनता के प्रति प्रत्यक्ष रूप से जवाबदेह होते हैं। लोक सेवक का मुख्य कार्य मंत्री को तटस्थ और विशेषज्ञ सलाह प्रदान करना तथा स्वीकृत नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करना है। लोक सेवक स्थायी कार्यपालिका का हिस्सा होते हैं जो पर्दे के पीछे रहकर कार्य करते हैं, जबकि मंत्री राजनीतिक कार्यपालिका के प्रमुख के रूप में नीतिगत निर्णयों हेतु संसद में जिम्मेदार होते हैं।

9. (C) नीतिगत निर्देश और आदेश
संगठनात्मक पदानुक्रम में अधोमुखी संचार का प्रवाह उच्च स्तर से निचले स्तर की ओर होता है। इस प्रक्रिया में वरिष्ठ अधिकारी अपने अधीनस्थों को नीतिगत निर्देश, कार्य संबंधी आदेश,

NODIA

(C) अधिकारियों का कानून की अवहेलना करने का अधिकार।
(D) मनमानी शक्ति की अनुपस्थिति।

271. 'विभागीय जांच' का एक मुख्य उद्देश्य है:
(A) प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन।
(B) कर्मचारी को तुरंत दंडित करना।
(C) कर्मचारी को पदोन्नत करना।
(D) कदाचार को छिपाना।

272. हर्बर्ट साइमन की 'सीमित तार्किकता' (बाउंडेड रेशनलिटी) की अवधारणा बताती है कि निर्णय लेने वाले:
(A) पूर्णतः तार्किक होते हैं।
(B) तार्किकता की सीमाओं के कारण 'संतोषजनक' विकल्प चुनते हैं।
(C) यादृच्छिक चुनाव करते हैं।
(D) सदैव पूर्ण और सटीक जानकारी रखते हैं।

273. संसद की 'लोक लेखा समिति' (PAC) किसका परीक्षण करती है?
(A) विभिन्न मंत्रालयों के बजट अनुमान।
(B) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्ट।
(C) कराधान के लिए सरकार के प्रस्ताव।
(D) कैबिनेट के नीतिगत निर्णय।

274. शिकायत निवारण के लिए 'संस्थागत बहुलवाद' की अवधारणा का अर्थ है:
(A) निवारण प्राप्त करने हेतु विविध संस्थाओं का होना।
(B) केवल एक शक्तिशाली संस्था का होना।
(C) शिकायत निवारण के लिए कोई संस्था न होना।
(D) ऐसी संस्थाओं का होना जो केवल विशिष्ट वर्ग की सेवा करती हों।

275. निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन शामिल हैं, एक को कथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है। सही उत्तर चुनिए।
कथन (A): उदारीकरण ने प्रशासन के समक्ष नवीन चुनौतियाँ प्रस्तुत की हैं।
कारण (R): राज्य की भूमिका नियंत्रक से सुगमकर्ता (इनेबलर) के रूप में परिवर्तित हो गई है।
(A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(D) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

276. किसी संगठन में अल्प मनोबल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण संकेतक क्या है?
(A) उच्च उत्पादकता और कम अनुपस्थिति।
(B) गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी।
(C) कर्मचारी शिकायतों की निम्न संख्या।
(D) उच्च कर्मचारी टर्नओवर और बार-बार होने वाले संघर्ष।

277. प्रशिक्षण के लिए 'सैंडविच कोर्स' में शामिल है:
(A) केवल व्यावहारिक कार्य-स्थल प्रशिक्षण।
(B) केवल सैद्धांतिक कक्षा व्याख्यान।
(C) संस्थागत और क्षेत्रीय प्रशिक्षण की वैकल्पिक अवधि।
(D) एक एकल, अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम।

278. भर्ती की 'योग्यता प्रणाली' (मेरिट सिस्टम) की एक प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है?
(A) राजनीतिक संबद्धता के आधार पर भर्ती।
(B) खुली प्रतियोगिता और सक्षमता के आधार पर चयन।
(C) आनुवंशिकता के आधार पर भर्ती।
(D) व्यक्तिगत मित्रता के आधार पर नियुक्ति।

279. वेबर के मॉडल को अक्सर 'आदर्श प्रारूप' कहा जाता है क्योंकि यह:
(A) वास्तविकता में एक पूर्णतः प्राप्त करने योग्य मॉडल है।
(B) संगठन के नैतिक रूप से श्रेष्ठ स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता है।
(C) व्यवहार में पाया जाने वाला संगठन का सबसे सामान्य रूप है।
(D) शुद्ध नौकरशाही विशेषताओं का एक वैचारिक निर्माण है।

280. सूची I को सूची II के साथ सुमेलित करें और सही उत्तर चुनें।
सूची I:
P. अभिभावक नौकरशाही
Q. जातीय नौकरशाही
R. संरक्षण नौकरशाही
S. योग्यता नौकरशाही
सूची II:
1. राजनीतिक पक्षपात (लूट पद्धति)
2. खुली प्रतिस्पर्धी परीक्षा
3. कुलीन या सामाजिक वर्ग की उत्पत्ति
4. उत्कृष्ट ज्ञान और गुण
(A) P-4, Q-3, R-1, S-2
(B) P-3, Q-4, R-2, S-1
(C) P-4, Q-1, R-3, S-2
(D) P-2, Q-3, R-1, S-4

281. मंत्री-लोक सेवक संबंध में, विधायिका के प्रति संवैधानिक रूप से कौन उत्तरदायी है?
(A) लोक सेवक
(B) प्रधानमंत्री कार्यालय
(C) मंत्री
(D) दोनों समान रूप से

282. एक संचार माध्यम के रूप में 'ग्रेपवाइन' की विशेषता है:
(A) तीव्र गति और विरूपण की संभावना।
(B) औपचारिकता और पूर्ण सटीकता।

Downloaded from www.pdf.tube

(C) धीमी गति और आधिकारिक स्वीकृति।
(D) केवल लिखित रिकॉर्ड का उपयोग।

283. 'विकास योजना' के मुख्य उद्देश्यों में से एक है:
(A) अनियोजित विकास को प्रोत्साहित करना।
(B) देश के आर्थिक ढांचे को कमजोर करना।
(C) क्षेत्रीय असंतुलन को बढ़ावा देना।
(D) राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार सीमित संसाधनों का आवंटन करना।

284. 'निष्पादन लेखापरीक्षा' (परफॉर्मेंस ऑडिट) नियमितता लेखापरीक्षा से आगे बढ़कर किसकी जांच करती है?
(A) केवल खातों की गणितीय सटीकता।
(B) मितव्ययिता, दक्षता और प्रभावशीलता।
(C) केवल लेनदेन की वैधता।
(D) संबंधित अधिकारियों की व्यक्तिगत संपत्ति।

285. निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन शामिल हैं, एक को कथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है। सही उत्तर चुनिए।
कथन (A): प्रशिक्षण एक सतत प्रक्रिया है।
कारण (R): कार्य की मांगें और तकनीक निरंतर परिवर्तित हो रही हैं।
(A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(D) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

286. निम्नलिखित में से कौन 'सामूहिक भ्रष्टाचार' का एक रूप है जहाँ भ्रष्टाचार तंत्र की गहराई तक समाया हुआ है?
(A) जबरन वसूली
(B) रिश्वतखोरी
(C) भाई-भतीजावाद
(D) प्रणालीगत भ्रष्टाचार

287. आरटीआई अधिनियम के तहत 'तृतीय पक्ष अपील' किसके विरुद्ध अपील को संदर्भित करती है?
(A) किसी तीसरे पक्ष से संबंधित सूचना का खुलासा करने के पी.आई.ओ. के निर्णय के विरुद्ध।
(B) आवेदक को सूचना देने से मना करने के विरुद्ध।
(C) सूचना प्रदान करने के लिए शुल्क लेने के विरुद्ध।
(D) सूचना प्रदान करने में विलंब करने के विरुद्ध।

288. ओम्बुड्समैन की संस्था का निर्माण किसकी ओर से प्रहरी के रूप में कार्य करने के लिए किया गया था?
(A) विधायिका के विरुद्ध कार्यपालिका।
(B) कार्यपालिका के विरुद्ध विधायिका।
(C) नागरिक के विरुद्ध विधायिका।
(D) कार्यपालिका के विरुद्ध न्यायपालिका।

289. पदोन्नति के लिए 'वरिष्ठता' सिद्धांत की सबसे बड़ी दुर्बलता यह है कि यह:
(A) बहुत अधिक व्यक्तिपरक है।
(B) योग्यता और श्रेष्ठ निष्पादन को हतोत्साहित करता है।
(C) प्रशासित करना अत्यंत कठिन है।
(D) पक्षपात उत्पन्न करता है।

290. संचार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. यह पूर्णतः एकतरफा प्रक्रिया है।
2. प्रभावशीलता के लिए प्रतिपुष्टि आवश्यक है।
3. 'शोर' संदेश को स्पष्ट करने में सहायक होता है।
उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) केवल 2
(B) केवल 1 और 2
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3

NODIA

291. नेतृत्व की कौन सी शैली लोगों और उत्पादन दोनों के प्रति उच्च सरोकार की विशेषता रखती है?
(A) दरिद्र प्रबंधन
(B) कंट्री क्लब प्रबंधन
(C) टीम प्रबंधन
(D) अधिकार-अनुपालन प्रबंधन

292. 'विकास प्रशासन' में नौकरशाही की प्राथमिक भूमिका कैसी होनी चाहिए?
(A) परिवर्तन के लिए अवरोधक।
(B) यथास्थिति की समर्थक।
(C) केवल नियंत्रण का साधन।
(D) परिवर्तन और आधुनिकीकरण का अभिकर्ता।

293. 'गिलोटिन' (Guillotine) एक संसदीय प्रक्रिया है जिसमें शामिल है:
(A) अनुदान की सभी मांगों पर विस्तृत चर्चा।
(B) बजट चर्चा के लिए समय में वृद्धि।
(C) अवशेष मांगों को एक साथ मतदान के लिए रखना।
(D) बजट को पूर्णतः अस्वीकार करना।

294. 'सुशासन' का सार किसमें निहित है?
(A) एक ही अधिकारी में शक्ति का संकेंद्रण।
(B) राज्य और नागरिकों के बीच संबंधों की गुणवत्ता।
(C) नियमों और विनियमों की पूर्ण अनुपस्थिति।
(D) नौकरशाही हितों की प्रधानता।

295. निम्नलिखित में से कौन प्रशासन में जवाबदेही सुनिश्चित करने का उपकरण नहीं है?
(A) सूचना का अधिकार
(B) सामाजिक लेखापरीक्षा
(C) ओम्बुड्समैन
(D) पूर्ण विवेकाधिकार और अत्यधिक गोपनीयता

296. अनुशासनात्मक कार्यवाही में एक कर्मचारी को 'कारण बताओ नोटिस' जारी किया जाता है:
(A) यह पूछने के लिए कि प्रस्तावित दंड क्यों न अधिरोपित किया जाए।
(B) उन्हें पदोन्नति के बारे में सूचित करने के लिए।
(C) उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन पर बधाई देने के लिए।
(D) उन्हें एक नवीन कार्य सौंपने के लिए।

297. 'नौकरशाही' की अवधारणा किस समाजशास्त्री के कार्य का केंद्र बिंदु है?
(A) कार्ल मार्क्स
(B) एमिल दुर्खीम
(C) मैक्स वेबर
(D) अगस्त कॉम्टे

298. लोक प्रशासन पर उदारीकरण के प्रभावों में से एक किसका बढ़ता उपयोग है?
(A) आउटसोर्सिंग और सेवाओं का अनुबंध देना।
(B) केंद्रीकृत आर्थिक नियोजन।
(C) राज्य के पूर्ण स्वामित्व वाले उद्यमों का विस्तार।
(D) लाइसेंस-परमिट प्रणाली का सुदृढ़ीकरण।

299. 'नियमितता लेखापरीक्षा' यह जाँचती है कि:
(A) व्यय के पीछे की नीति सही थी या नहीं।
(B) व्यय केवल मितव्ययिता को ध्यान में रखकर किया गया था।
(C) व्यय ने इच्छित परिणाम प्राप्त किए।
(D) व्यय स्थापित नियमों और स्वीकृतियों के अनुरूप है।

300. लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 किसके नेतृत्व में हुए भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के पश्चात लागू हुआ?
(A) जयप्रकाश नारायण
(B) अन्ना हजारे
(C) मेधा पाटेकर
(D) विनोबा भावे

www.nodia.in

Click Here to Buy book on Amazon

(D) भर्ती

258. संगठन के 'शास्त्रीय' सिद्धांत कर्मचारियों को किस रूप में देखते हैं?
(A) मशीन के पुर्जे, जो आर्थिक प्रोत्साहनों से अभिप्रेरित होते हैं।
(B) रचनात्मक और स्व-प्रेरित व्यक्ति।
(C) जटिल सामाजिक प्राणी।
(D) संगठन की सर्वाधिक मूल्यवान संपत्ति।

259. नीति निर्माण में एक लोक सेवक की भूमिका आदर्श रूप से क्या होनी चाहिए?
(A) अंतिम नीतिगत निर्णय लेना।
(B) मंत्री की राजनीतिक प्राथमिकताओं की उपेक्षा करना।
(C) मंत्री के समक्ष तथ्यों और विकल्पों को प्रस्तुत करना।
(D) अपनी व्यक्तिगत पसंदीदा नीति को लागू करना।

260. 'सुशासन' के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. यह केवल प्रशासनिक दक्षता से संबंधित है।
2. इसमें विधि का शासन, पारदर्शिता और भागीदारी सम्मिलित है।
3. इसका उद्देश्य भ्रष्टाचार को कम करना और संवेदनशील होना है।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3

261. 'नवीन सार्वजनिक प्रबंधन' (NPM) दृष्टिकोण किसका समर्थन करता है?
(A) अधिक पदानुक्रम और केंद्रीकरण।
(B) नौकरशाही के आकार का विस्तार करना।
(C) नागरिकों को 'ग्राहकों' के रूप में मानना।
(D) नियमों की संख्या में वृद्धि करना।

262. सी.ए.जी. (CAG) द्वारा प्रस्तुत लेखापरीक्षा की अंतिम रिपोर्ट किसे सौंपी जाती है?
(A) प्रधानमंत्री को।
(B) राष्ट्रपति को, संसद के समक्ष रखे जाने हेतु।
(C) वित्त मंत्री को।
(D) सर्वोच्च न्यायालय को।

263. भ्रष्टाचार के विरुद्ध 'सामाजिक दंड' में क्या शामिल होगा?
(A) कारावास जैसा कानूनी दंड।
(B) विभागीय जांच।
(C) मौद्रिक जुर्माना।
(D) सार्वजनिक निंदा और सामाजिक बहिष्कार।

264. सूचना के अधिकार अधिनियम का प्राथमिक उद्देश्य नागरिकों को किसलिए सशक्त बनाना है?
(A) सरकार के कामकाज पर प्रश्न उठाने के लिए।
(B) सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए।
(C) अन्य नागरिकों की व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने के लिए।
(D) राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों में हस्तक्षेप के लिए।

265. कार्मिक प्रशासन के निम्नलिखित कार्यों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करें:
1. पदोन्नति
2. प्रशिक्षण
3. भर्ती
4. सेवानिवृत्ति

(A) 3, 2, 1, 4
(B) 2, 3, 1, 4
(C) 3, 1, 2, 4
(D) 1, 2, 3, 4

266. निम्नलिखित में से कौन विकास प्रशासन की विशेषता नहीं है?
(A) यथास्थितिवादी उन्मुखीकरण
(B) परिवर्तन-उन्मुखीकरण
(C) लक्ष्य-उन्मुखीकरण
(D) नागरिक-भागीदारी उन्मुखीकरण

267. निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें।
कथन I: भारतीय नौकरशाही की अक्सर अभिजात वर्गवादी होने के कारण आलोचना की जाती है।
कथन II: विकास के लिए एक सहानुभूतिपूर्ण और संवेदनशील नौकरशाही की आवश्यकता है।
(A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं।
(C) कथन I सत्य है लेकिन कथन II असत्य है।
(D) कथन I असत्य है लेकिन कथन II सत्य है।

268. 'प्रतिबद्ध नौकरशाही' (कमिटेड ब्यूरोक्रेसी) का विचार किसके प्रति प्रतिबद्धता का समर्थन करता है?
(A) सत्ताधारी दल की विचारधारा।
(B) राष्ट्रीय विकास और संवैधानिक सिद्धांत।
(C) व्यक्तिगत करियर की प्रगति।
(D) अपनी जाति के हित।

269. 'मौखिक' संचार की तुलना में 'लिखित' संचार का मुख्य लाभ यह है कि यह:
(A) तीव्र है और तत्काल प्रतिपुष्टि की अनुमति देता है।
(B) अनौपचारिक और व्यक्तिगत है।
(C) एक स्थायी रिकॉर्ड प्रदान करता है और सटीकता सुनिश्चित करता है।
(D) कम खर्चीला है।

270. 'विधि के शासन' (Rule of Law) का एक प्रमुख पहलू है:
(A) शासक की सर्वोच्चता।
(B) अलग-अलग व्यक्तियों के लिए अलग-अलग कानून।

NODIA

संगठनात्मक लक्ष्य और नियमों की जानकारी प्रदान करते हैं। यह संचार व्यवस्था संगठन में अनुशासन बनाए रखने और कार्यों के समन्वय हेतु अनिवार्य है। सुझाव योजनाएं और शिकायत रिपोर्ट उर्ध्वमुखी संचार के उदाहरण हैं, जो निचले स्तर से ऊपर की ओर प्रेषित किए जाते हैं, जबकि नीतिगत स्पष्टीकरण सदैव प्रबंधन द्वारा नीचे की ओर जाते हैं।

10. (A) P-3, Q-4, R-1, S-2
लूट पद्धति में नियुक्तियां योग्यता के बजाय राजनीतिक निष्ठा के आधार पर की जाती हैं, जबकि योग्यता प्रणाली केवल सक्षम उम्मीदवारों के चयन पर केंद्रित होती है। पद वर्गीकरण के अंतर्गत प्रत्येक पद के कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का वस्तुनिष्ठ विश्लेषण करके उन्हें श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। सामूहिक सौदेबाजी एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ कर्मचारी प्रतिनिधि और प्रबंधन मिलकर कार्य की शर्तों पर वार्ता करते हैं। ये सभी अवधारणाएं कार्मिक प्रशासन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती हैं, जिनका उद्देश्य संगठनात्मक ढांचे को सुदृढ़ बनाना है।

11. (D) प्रत्येक वर्ष इसकी संपूर्णता में औचित्य सिद्ध करना।
शून्य-आधारित बजटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बजट तैयार करते समय पिछले वर्ष के आंकड़ों को आधार नहीं माना जाता है। इसके विपरीत, प्रत्येक नए वित्तीय वर्ष के लिए हर विभागीय कार्यक्रम और गतिविधि का नए सिरे से मूल्यांकन किया जाता है। विभाग को यह सिद्ध करना होता है कि किसी विशिष्ट कार्य के लिए धन की आवश्यकता क्यों है। यह पद्धति संसाधनों के आवंटन में मितव्ययिता लाती है और अनुपयोगी कार्यक्रमों को समाप्त करने में सहायक होती है, जिससे बजटीय पारदर्शिता में वृद्धि होती है।

12. (B) सार्वजनिक प्राधिकरण में पारदर्शिता और जवाबदेही।
सूचना का अधिकार अधिनियम का मुख्य दर्शन शासन में खुलापन और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना है। यह कानून नागरिकों को सरकारी अभिलेखों और निर्णयों तक पहुँच प्रदान करके प्रशासन को अधिक जवाबदेह बनाता है। जब जनता को सरकारी कार्यों की जानकारी होती है, तो भ्रष्टाचार की संभावना कम हो जाती है और लोकतांत्रिक मूल्य सुदृढ़ होते हैं। यह अधिनियम लोक सेवकों की विवेकाधीन शक्तियों पर अंकुश लगाने और उन्हें जनता के प्रति संवेदनशील बनाने में एक क्रांतिकारी उपकरण के रूप में कार्य करता है।

13. (C) कुप्रशासन के विरुद्ध शिकायतों की जांच करना।
ओम्बुड्समैन या लोकपाल की संस्था का प्राथमिक उद्देश्य नागरिकों को सरकारी तंत्र के कुप्रशासन, पक्षपात और भ्रष्टाचार से बचाना है। यह एक स्वतंत्र निकाय के रूप में कार्य करता है जो जनता की शिकायतों को सुनता है और संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध जांच करता है। इसकी उपस्थिति से प्रशासन में शुचिता बनी रहती है और आम जनता का लोकतांत्रिक संस्थाओं में विश्वास सुदृढ़ होता है। यह संस्था दंड देने के बजाय व्यवस्था में सुधार और जवाबदेही सुनिश्चित करने पर अधिक बल देती है।

14. (D) विन्सेंट डी गोर्ने
'ब्यूरोक्रेसी' या नौकरशाही शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 18वीं शताब्दी के मध्य में फ्रांसीसी अर्थशास्त्री विन्सेंट डी गोर्ने द्वारा किया गया था। उन्होंने इस शब्द का उपयोग उस समय की सरकारी कार्यप्रणाली में व्याप्त कठोरता और मेजों पर होने वाले शासन के वर्णन हेतु किया था। यद्यपि मैक्स वेबर ने बाद में इस अवधारणा का विस्तृत और शास्त्रीय विश्लेषण किया, किंतु शब्द की उत्पत्ति का श्रेय गोर्ने को ही जाता है। यह शब्द फ्रांसीसी 'ब्यूरो' और ग्रीक 'क्रेटोस' से मिलकर बना है।

15. (A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
मनोबल एक मानसिक अवस्था है जो कर्मचारी की कार्य के प्रति निष्ठा और समूह के साथ सहयोग करने की भावना को निर्धारित करती है। जब कर्मचारियों का मनोबल उच्च होता है, तो वे अधिक ऊर्जा और उत्साह के साथ लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, जिसका सीधा सकारात्मक प्रभाव संगठन की उत्पादकता पर पड़ता है। इस प्रकार, उत्पादकता और मनोबल के बीच गहरा अंतर्संबंध होता है क्योंकि एक संतुष्ट और अभिप्रेरित कर्मचारी सदैव अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन अधिक कुशलतापूर्वक करता है।

16. (B) कोचिंग (मार्गदर्शन)
कार्य-स्थल पर प्रशिक्षण या कार्य-पर पद्धति में कर्मचारी को वास्तविक कार्य वातावरण में कार्य करते हुए कौशल सिखाया जाता है। मार्गदर्शन या कोचिंग इस पद्धति का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जहाँ एक अनुभवी वरिष्ठ अधिकारी अपने अधीनस्थ को निरंतर निर्देश और प्रतिपुष्टि प्रदान करता है। इससे कर्मचारी कार्य की बारीकियों को व्यावहारिक रूप से समझ पाता है और तत्काल अपनी त्रुटियों में सुधार कर सकता है। व्याख्यान और मामला अध्ययन जैसी विधियां कक्षा आधारित या कार्य-बाह्य होती हैं, क्योंकि वे कार्य स्थल से अलग आयोजित की जाती हैं।

17. (B) राज्य की भूमिका में एक सुगमकर्ता और नियामक के रूप में बदलाव।
उदारीकरण की प्रक्रिया ने लोक प्रशासन के पारंपरिक स्वरूप को पूरी तरह परिवर्तित कर दिया है। अब राज्य आर्थिक गतिविधियों का प्रत्यक्ष संचालक होने के बजाय एक सुगमकर्ता और नियामक की भूमिका निभा रहा है। इसका अर्थ है कि सरकार अब निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने हेतु अनुकूल वातावरण तैयार करती है और बाजार की प्रतिस्पर्धा को नियंत्रित करने हेतु नियम बनाती है। इस बदलाव से प्रशासनिक कार्यकुशलता में सुधार आया है और सार्वजनिक-निजी भागीदारी जैसी नई अवधारणाओं को शासन व्यवस्था में प्रमुख स्थान मिला है।

18. (A) यह सुनिश्चित करना कि व्यय नियमों और उचित मितव्ययिता के अनुरूप हो।
वित्तीय प्रशासन में लेखापरीक्षा का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक धन के व्यय की वैधता और नियमितता की जाँच करना है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि आवंटित धनराशि उसी उद्देश्य हेतु व्यय की गई है जिसके लिए विधायिका ने अनुमति दी थी।

NODIA

इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा यह भी देखती है कि क्या व्यय के दौरान मितव्ययिता और वित्तीय बुद्धिमत्ता का पालन किया गया है। यह सरकारी जवाबदेही सुनिश्चित करने का एक सशक्त उपकरण है, जो भ्रष्टाचार को रोकने और बजटीय नियंत्रण बनाए रखने में सहायक होता है।

19. (C) सी.वी.सी. - शिकायत निवारण के लिए एक संवैधानिक निकाय।
केंद्रीय सतर्कता आयोग मूल रूप से एक वैधानिक निकाय है, संवैधानिक नहीं। इसकी स्थापना 1964 में संथानम समिति की सिफारिशों पर भ्रष्टाचार को रोकने और केंद्र सरकार के भीतर सतर्कता गतिविधियों की निगरानी हेतु की गई थी। दूसरी ओर, लोकपाल और लोकायुक्त क्रमशः राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर भ्रष्टाचार विरोधी प्रहरी के रूप में कार्य करते हैं। ओम्बुड्समैन की अवधारणा वास्तव में स्वीडन से ही वैश्विक स्तर पर प्रसारित हुई है। अतः केंद्रीय सतर्कता आयोग को संवैधानिक कहना तकनीकी रूप से त्रुटिपूर्ण है।

20. (C) केवल 1 और 3
सुशासन की अवधारणा केवल आर्थिक विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि यह शासन की गुणवत्ता और नागरिक कल्याण पर केंद्रित है। इसमें नागरिकों की सक्रिय भागीदारी, विधि का शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही जैसे महत्वपूर्ण स्तंभ सम्मिलित हैं। सुशासन सुनिश्चित करता है कि निर्णय प्रक्रिया समावेशी हो और संसाधनों का उपयोग न्यायसंगत तरीके से किया जाए। यद्यपि आर्थिक वृद्धि इसका एक परिणाम हो सकती है, किंतु इसकी मुख्य चिंता प्रशासनिक संवेदनशीलता और संस्थाओं की प्रभावशीलता को निरंतर बढ़ावा देना है।

21. (C) विशेषक (ट्रेट) सिद्धांत
नेतृत्व का विशेषक सिद्धांत इस पारंपरिक धारणा पर आधारित है कि कुछ व्यक्ति जन्मजात रूप से नेतृत्व के गुणों के साथ पैदा होते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार, साहस, बुद्धिमत्ता, आत्मविश्वास और करिश्मा जैसे विशेष लक्षण व्यक्ति को एक सफल नेता बनाते हैं। यह मानता है कि ये गुण शिक्षा या प्रशिक्षण के माध्यम से अर्जित नहीं किए जा सकते। यद्यपि आधुनिक सिद्धांत इस विचार को चुनौती देते हैं, किंतु ऐतिहासिक रूप से इसने महान नेताओं के व्यक्तित्व का विश्लेषण करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

22. (B) यह लक्ष्य विस्थापन की ओर ले जाता है जहाँ नियम साध्य बन जाते हैं।
रॉबर्ट मर्टन जैसे विचारकों ने वेबर के मॉडल की आलोचना करते हुए तर्क दिया कि नियमों पर अत्यधिक बल देने से कर्मचारी वास्तविक लक्ष्यों को विस्मृत कर देते हैं। इस प्रक्रिया में नियमों का पालन करना ही अंतिम उद्देश्य बन जाता है, जिसे लक्ष्य विस्थापन कहा जाता है। यह स्थिति नौकरशाही को कठोर और यंत्रवत बना देती है, जिससे वह जनता की आवश्यकताओं के प्रति असंवेदनशील हो जाती है। इसके परिणामस्वरूप प्रशासनिक दक्षता घटने लगती है और नियमों की जटिलता नवाचार और त्वरित समाधानों में बाधक बनती है।

23. (D) किसी विशेष श्रेणी में कर्मचारी की सेवा की अवधि।
वरिष्ठता का सिद्धांत पदोन्नति की एक ऐसी पद्धति है जहाँ किसी कर्मचारी की सेवा के वर्षों या अनुभव की अवधि को ही मुख्य मानदंड माना जाता है। यह प्रणाली पूरी तरह वस्तुनिष्ठ है क्योंकि इसमें पक्षपात या व्यक्तिगत पसंद की संभावना बहुत कम होती है। यह कर्मचारियों में सुरक्षा की भावना पैदा करती है और लंबी सेवा के प्रति उनके समर्पण को मान्यता प्रदान करती है। यद्यपि इसमें नवीन योग्यता की उपेक्षा होने का जोखिम रहता है, फिर भी इसे इसके सरल और स्पष्ट कार्यान्वयन के कारण व्यापक रूप से अपनाया जाता है।

24. (C) कथन I असत्य है लेकिन कथन II सत्य है।
अनुशासन का अर्थ केवल दंड देना नहीं है, बल्कि यह संगठन के नियमों और आचरण संहिताओं के पालन की एक सकारात्मक व्यवस्था है। इसका वास्तविक उद्देश्य कर्मचारियों के व्यवहार में सुधार करना और उन्हें संगठनात्मक लक्ष्यों के अनुरूप ढालना है। अनुशासनात्मक कार्रवाई तब की जाती है जब सुधार के अन्य सभी प्रयास विफल हो जाते हैं। इसलिए, इसे दंडात्मक होने के बजाय सुधारात्मक माना जाता है, ताकि कर्मचारी अपनी त्रुटियों को सुधारकर संगठन की उत्पादकता और प्रतिष्ठा को बनाए रखने में अपना योगदान दे सके।

25. (B) 2, 1, 4, 3
अनुशासनात्मक प्रक्रिया की शुरुआत प्रारंभिक जांच से होती है, जिसमें यह निर्धारित किया जाता है कि क्या आरोपों में कोई ठोस तथ्य है। इसके पश्चात संबंधित कर्मचारी को आरोपों का विवरण देते हुए आरोप-पत्र जारी किया जाता है। यदि कर्मचारी का उत्तर संतोषजनक नहीं होता, तो विस्तृत तथ्यों के अन्वेषण हेतु औपचारिक जांच की जाती है। अंत में, जांच रिपोर्ट के निष्कर्षों के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा उचित दंड अधिरोपित किया जाता है। यह क्रम प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों और निष्पक्षता को सुनिश्चित करने हेतु अनिवार्य है।

26. (A) जातीय नौकरशाही
एफ.एम. मार्क्स के अनुसार जातीय नौकरशाही वह प्रणाली है जहाँ सरकारी पदों पर भर्ती उम्मीदवारों की योग्यता के बजाय उनके विशिष्ट सामाजिक वर्ग या जातिगत स्थिति के आधार पर की जाती है। इस प्रकार की व्यवस्था में सत्ता और प्रशासनिक उत्तरदायित्व समाज के एक विशेष अभिजात वर्ग तक ही सीमित रहते हैं। यह प्रणाली सामाजिक असमानता को सुदृढ़ करती है और लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत कार्य करती है। यहाँ व्यक्तिगत क्षमता गौण हो जाती है और जन्म या सामाजिक स्थिति ही करियर के अवसरों का मुख्य निर्धारण करती है।

27. (D) संसाधनों और प्रशिक्षित जनशक्ति की प्रचुरता।
विकासशील देशों की नौकरशाही के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती वास्तव में संसाधनों की कमी और प्रशिक्षित जनशक्ति का अभाव है। अत्यधिक केंद्रीकरण और नियमों की कठोरता अक्सर विकास परियोजनाओं में विलंब का कारण बनती है। भ्रष्टाचार और जवाबदेही की कमी भी प्रशासनिक प्रभावशीलता को कम करती है। इसके अतिरिक्त, नौकरशाहों का दृष्टिकोण कभी-कभी परिवर्तन के प्रति नकारात्मक होता है। इसलिए,

Downloaded from www.pdf.tube

प्रशिक्षित जनशक्ति और संसाधनों की प्रचुरता कोई चुनौती नहीं, बल्कि विकास हेतु आवश्यक समाधान है जो इन देशों में प्रायः अनुपलब्ध होते हैं।

28. (B) किए गए कार्य, कार्यक्रम और गतिविधियाँ।
निष्पादन बजटिंग एक आधुनिक बजटीय तकनीक है जो केवल खर्च की मदों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय कार्यों के परिणामों पर बल देती है। यह इनपुट के स्थान पर आउटपुट को प्राथमिकता देती है। इसमें सरकारी विभागों द्वारा किए जाने वाले कार्यक्रमों और गतिविधियों का भौतिक मूल्यांकन किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सार्वजनिक धन का उपयोग विशिष्ट लक्ष्यों और सामाजिक लाभों को प्राप्त करने हेतु कुशलतापूर्वक किया जा रहा है, जिससे वित्तीय जवाबदेही और पारदर्शिता में निरंतर वृद्धि होती है।

29. (B) हितधारकों की शिकायतों को हल करने की प्रणाली।
प्रशासन के संदर्भ में शिकायत निवारण एक ऐसा तंत्र है जिसके माध्यम से नागरिक या कर्मचारी प्रशासनिक कार्यों, सेवाओं या निर्णयों के प्रति अपना असंतोष व्यक्त कर सकते हैं। यह प्रणाली इन शिकायतों की निष्पक्ष जांच और त्वरित समाधान सुनिश्चित करती है। प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र प्रशासन को अधिक उत्तरदायी, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित बनाता है। यह लोकतंत्र में जनता और सरकार के बीच विश्वास के सेतु का कार्य करता है। लोकपाल, सूचना का अधिकार और नागरिक चार्टर इस व्यवस्था को सुदृढ़ करने के महत्वपूर्ण उपकरण हैं।

30. (D) प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग।
भारत में लोकपाल और लोकायुक्त की संस्थाओं की स्थापना की सर्वप्रथम सिफारिश 1966 में मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में गठित प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने की थी। आयोग का मानना था कि नागरिकों की समस्याओं और भ्रष्टाचार के निवारण हेतु स्कैंडिनेवियाई देशों की भांति एक ओम्बुड्समैन जैसी स्वतंत्र संस्था आवश्यक है। यद्यपि इस कानून को संसद द्वारा पारित होने में कई दशक लग गए, किंतु इसकी वैचारिक नींव इसी आयोग की रिपोर्ट द्वारा रखी गई थी, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक जीवन में शुचिता लाना था।

31. (A) लिखित और औपचारिक माध्यम।
नौकरशाही संरचना में संचार की मुख्य विशेषता इसकी औपचारिकता और लिखित प्रलेखों पर निर्भरता है। पदानुक्रम के नियमों के अनुसार, समस्त आदेश, निर्देश और सूचनाएं फाइलों, ज्ञापनों और परिपत्रों के माध्यम से प्रवाहित होती हैं। यह व्यवस्था भविष्य के संदर्भ, जवाबदेही सुनिश्चित करने और विधिक प्रमाण बनाए रखने हेतु आवश्यक है। यद्यपि अनौपचारिक संचार भी मौजूद होता है, किंतु आधिकारिक निर्णयों और संचार हेतु केवल औपचारिक माध्यमों को ही वैध माना जाता है, जो संगठन में स्थिरता और स्पष्टता प्रदान करते हैं।

32. (B) एक राजनीतिक प्रमुख और एक स्थायी कार्यपालिका।
मंत्री और लोक सेवक के बीच का संबंध संसदीय लोकतंत्र के मूल सिद्धांत को दर्शाता है। मंत्री निर्वाचित होकर आते हैं और विभाग के राजनीतिक प्रमुख के रूप में नीतियों का निर्धारण करते हैं, जबकि लोक सेवक स्थायी कार्यपालिका का हिस्सा होते हैं जो अपनी विशेषज्ञता के आधार पर उन नीतियों को लागू करते हैं। मंत्री जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जबकि लोक सेवक पर्दे के पीछे रहकर प्रशासनिक निरंतरता सुनिश्चित करते हैं। इन दोनों के बीच समन्वय ही कुशल और प्रभावी शासन की अनिवार्य शर्त है।

33. (B) आंतरिक पदोन्नति।
अप्रत्यक्ष भर्ती या आंतरिक पदोन्नति वह प्रक्रिया है जिसमें संगठन के भीतर रिक्त उच्च पदों को निचले स्तर पर कार्यरत योग्य कर्मचारियों के माध्यम से भरा जाता है। इसे अप्रत्यक्ष इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें बाहरी उम्मीदवारों को अवसर नहीं मिलता। यह पद्धति कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाती है और उन्हें संगठन के प्रति वफादार रहने हेतु प्रेरित करती है। इसके विपरीत, समाचार पत्रों में विज्ञापन देना और परिसर साक्षात्कार प्रत्यक्ष भर्ती के उदाहरण हैं, जहाँ बाहरी प्रतिभाओं को सीधे संगठन में सम्मिलित किया जाता है।

34. (A) नौकरशाही में लक्ष्य विस्थापन।
जब कोई लोक सेवक सेवा के मूल उद्देश्यों और नागरिक कल्याण के स्थान पर केवल नियमों के अक्षरशः पालन को ही अपना परम कर्तव्य मान लेता है, तो इसे लक्ष्य विस्थापन कहा जाता है। इस स्थिति में नियम साधन होने के बजाय स्वयं साध्य बन जाते हैं। यह अक्सर व्यक्तिगत सुरक्षा और दंड के भय से उत्पन्न होता है। इसके परिणामस्वरूप प्रशासन में विलंब, संवेदनहीनता और लालफीताशाही में वृद्धि होती है। यह नौकरशाही की एक ऐसी विकृति है जो विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में सबसे बड़ी बाधा बनकर उभरती है।

35. (A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।
लूट पद्धति में निर्वाचित नेता अपने समर्थकों को सरकारी पदों पर नियुक्त करते हैं, जिससे प्रशासन पर उनका प्रत्यक्ष राजनीतिक नियंत्रण स्थापित हो जाता है। यद्यपि यह व्यवस्था वफादारी सुनिश्चित करती है, किंतु इसमें सक्षमता की कमी हो सकती है। इसके विपरीत, योग्यता प्रणाली में नियुक्तियां निष्पक्ष प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं और कौशल के आधार पर की जाती हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सिविल सेवा को राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त रखकर एक पेशेवर और तटस्थ प्रशासनिक ढांचा तैयार करना है, जो किसी भी दल की सरकार के साथ कार्य कर सके।

36. (D) व्यक्तिगत और भावनात्मक संबंध
मैक्स वेबर की आदर्श नौकरशाही का आधार पूर्णतः तार्किक और निर्वैयक्तिक है। इसमें व्यक्तिगत भावनाओं, पारिवारिक संबंधों या भावनात्मक जुड़ाव हेतु कोई स्थान नहीं होता। समस्त प्रशासनिक कार्य पूर्व-निर्धारित लिखित नियमों के अनुसार किए जाते हैं ताकि निष्पक्षता बनी रहे। सत्ता का स्पष्ट पदानुक्रम और श्रम का विशेषीकरण इसकी अन्य प्रमुख विशेषताएं हैं। वेबर के

NODIA

में वृद्धि होती है। यह न केवल उनके व्यक्तिगत करियर विकास में सहायक है, बल्कि इससे संपूर्ण संगठन की प्रभावशीलता भी सुधरती है। इससे लोक सेवक जनता की समस्याओं को अधिक कुशलता से सुलझा पाते हैं।

107. (D) एक क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत निष्पादन रिपोर्ट।
उर्ध्वमुखी संचार संगठन के निचले स्तरों से उच्च प्रबंधन की ओर सूचनाओं का प्रवाह है। जब एक क्षेत्रीय अधिकारी अपने कार्यों की रिपोर्ट मुख्यालय प्रेषित करता है, तो वह अपने वरिष्ठों को जमीनी वास्तविकता और प्रगति की जानकारी प्रदान कर रहा होता है। यह संचार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है क्योंकि यह शीर्ष अधिकारियों को नीतियों के प्रभाव का मूल्यांकन करने और भविष्य के निर्णय लेने में सहायता करता है। इसमें सुझाव, शिकायतें और प्रतिपुष्टि भी सम्मिलित होते हैं। यह व्यवस्था संगठन में सूचना के स्वतंत्र प्रवाह को सुनिश्चित करती है।

108. (B) कार्यों और निर्णयों के लिए उत्तर देने का दायित्व।
लोक प्रशासन में जवाबदेही का अर्थ है कि लोक सेवकों और राजनेताओं को उनके द्वारा की गई कार्रवाइयों और लिए गए निर्णयों हेतु जनता, संसद या कानून के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। इसका तात्पर्य है कि यदि कोई अधिकारी अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता है या कर्तव्यों में लापरवाही बरतता है, तो उसे उसके परिणामों का सामना करना होगा। जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु सूचना का अधिकार, लेखापरीक्षा और न्यायिक समीक्षा जैसे तंत्र विद्यमान हैं। यह सुशासन का प्राण है क्योंकि इसके बिना सत्ता निरंकुश और भ्रष्ट हो सकती है।

109. (D) जुर्माना लगाना
मनोबल एक मानसिक और भावनात्मक स्थिति है जिसे मापने हेतु मनोवैज्ञानिक और संगठनात्मक तकनीकों का उपयोग किया जाता है। मनोवृत्ति सर्वेक्षण और साक्षात्कार के माध्यम से कर्मचारियों की संतुष्टि का आकलन किया जा सकता है। उत्पादकता प्रलेख और अनुपस्थिति की दर भी मनोबल के अप्रत्यक्ष संकेतक होते हैं। इसके विपरीत, जुर्माना लगाना एक दंडात्मक कार्रवाई है जिसका उद्देश्य अनुशासन बनाए रखना है, न कि मनोबल मापना। यद्यपि अत्यधिक जुर्माना लगाने से मनोबल गिर सकता है, किंतु यह स्वयं मनोबल मापने का कोई वैज्ञानिक तरीका नहीं माना जाता है।

110. (A) केवल 1 और 2
मैक्स वेबर ने नौकरशाही को आधुनिक समाज का सर्वाधिक तार्किक और कुशल संगठन माना था, जो विधिक नियमों पर आधारित होता है। यद्यपि, आलोचकों का तर्क है कि नौकरशाही प्रायः अपनी कठोरता, लालफीताशाही और बदलती परिस्थितियों के प्रति अनुकूलन न कर पाने की दुर्बलता से ग्रस्त रहती है। इसके विपरीत, संरक्षण नौकरशाही योग्यता पर नहीं, बल्कि राजनीतिक वफादारी और पक्षपात पर आधारित होती है, जहाँ नियुक्तियां 'लूट पद्धति' की भांति की जाती हैं। अतः संरक्षण प्रणाली को योग्यता आधारित कहना तकनीकी रूप से त्रुटिपूर्ण है।

111. (A) चीनी मंदारिन।
एफ.एम. मार्क्स के अनुसार अभिभावक नौकरशाही वह है जो स्वयं को लोकहित का संरक्षक और समाज का मार्गदर्शक मानती है। इसका ऐतिहासिक रूप से श्रेष्ठ उदाहरण प्राचीन चीन की मंदारिन प्रणाली है। इन अधिकारियों का चयन अत्यंत कठिन परीक्षाओं के माध्यम से होता था और वे उत्कृष्ट ज्ञान तथा नैतिक गुणों से संपन्न माने जाते थे। उनका विश्वास था कि वे जनता के कल्याण हेतु सर्वश्रेष्ठ निर्णय लेने में सक्षम हैं। यद्यपि यह प्रणाली कुशल थी, किंतु इसमें लोकतांत्रिक जवाबदेही का अभाव था क्योंकि नौकरशाह स्वयं को जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं मानते थे।

112. (B) न्यूनतम वरिष्ठता रखने वालों में योग्यता मुख्य कारक है।
वरिष्ठता-सह-योग्यता का सिद्धांत पदोन्नति का एक संतुलित दृष्टिकोण है। इसमें केवल वे कर्मचारी पदोन्नति के पात्र माने जाते हैं जिन्होंने सेवा की एक न्यूनतम निर्धारित अवधि पूर्ण कर ली हो। एक बार जब उम्मीदवार इस पात्रता को पार कर लेते हैं, तो उनमें से सर्वश्रेष्ठ का चयन उनकी योग्यता, कार्य प्रदर्शन और क्षमता के आधार पर किया जाता है। यह प्रणाली वरिष्ठता के सम्मान और योग्यता की अनिवार्यता के बीच समन्वय स्थापित करती है, जिससे अनुभवी और सक्षम दोनों प्रकार के कर्मचारियों को न्याय प्राप्त होता है और प्रशासनिक गुणवत्ता बनी रहती है।

113. (A) राजनीतिक रूप से प्रतिबद्ध नौकरशाही की बढ़ती मांग।
पारंपरिक रूप से नौकरशाही से यह अपेक्षा की जाती है कि वह राजनीतिक रूप से तटस्थ रहे और किसी भी विचारधारा की सरकार के साथ निष्पक्षता से कार्य करे। यद्यपि, वर्तमान समय में यह प्रवृत्ति देखी जा रही है कि राजनीतिक नेतृत्व उन अधिकारियों को प्राथमिकता देता है जो उनकी विशिष्ट विचारधारा या लक्ष्यों के प्रति व्यक्तिगत रूप से प्रतिबद्ध हों। यह मांग 'स्थायी और तटस्थ' सिविल सेवा के मूल सिद्धांत हेतु एक बड़ी चुनौती है। इससे पक्षपात और प्रशासनिक गिरावट का जोखिम बढ़ जाता है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों और वस्तुनिष्ठ निर्णय प्रक्रिया को दुर्बल कर सकता है।

114. (A) विकल्पों में से कार्ययोजना चुनने की प्रक्रिया।
निर्णय-प्रक्रिया प्रशासन का हृदय है, जिसमें किसी समस्या के समाधान हेतु उपलब्ध विभिन्न विकल्पों का विश्लेषण किया जाता है। एक प्रशासक को प्रत्येक विकल्प के लाभों और हानियों का मूल्यांकन करना होता है और अंततः उस विकल्प का चयन करना होता है जो संगठन के लक्ष्यों और सार्वजनिक हित हेतु सर्वोत्तम हो। हर्बर्ट साइमन के अनुसार, यह एक तार्किक प्रक्रिया है जिसमें सूचनाओं का संग्रह और उनका तार्किक प्रसंस्करण सम्मिलित होता है। प्रभावी निर्णय लेना न केवल प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाता है, बल्कि संसाधनों के सटीक उपयोग को भी निर्धारित करता है।

115. (C) शासन और नियामक कार्य।
उदारीकरण के युग में लोक प्रशासन का ध्यान प्रत्यक्ष आर्थिक भागीदारी से हटकर अब सुशासन और प्रभावी नियमन की ओर केंद्रित हो गया है। सरकार अब स्वयं व्यापार करने के बजाय बाजार की गतिविधियों को व्यवस्थित करने हेतु नियम और

Click Here to Buy book on Amazon

वातावरण निर्मित करे जहाँ कर्मचारियों का मनोबल उच्च बना रहे, ताकि उत्पादकता में निरंतरता रहे।

46. (D) अनौपचारिक सामाजिक मेलजोल
कर्मचारी-नियोक्ता संबंधों में औपचारिक पद्धतियां वे हैं जो विधिक या संगठनात्मक नियमों द्वारा स्थापित की जाती हैं। संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र और ह्विटली परिषदें विवादों को सुलझाने और सहयोग बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा निर्मित विधिवत संस्थाएं हैं। सामूहिक सौदेबाजी भी एक स्थापित प्रक्रिया है जहाँ वेतन और सेवा शर्तों पर वार्ता होती है। इसके विपरीत, अनौपचारिक सामाजिक मेलजोल जैसे उत्सव मनाना या खेलकूद, आपसी समझ तो बढ़ाते हैं, किंतु वे औपचारिक संबंधों या नीतिगत निर्णयों के आधिकारिक माध्यम नहीं माने जाते हैं।

47. (A) भ्रष्टाचार का मुकाबला करना और प्रशासन में सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करना।
केंद्रीय सतर्कता आयोग भारत में सतर्कता के क्षेत्र में शीर्ष संस्था है। इसका प्राथमिक उत्तरदायित्व केंद्र सरकार के विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों में भ्रष्टाचार की रोकथाम करना है। यह लोक सेवकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच का पर्यवेक्षण करता है और प्रशासन में नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने हेतु नीतियां निर्मित करता है। यह भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत जांच की निगरानी भी करता है। इसकी निष्पक्षता सुनिश्चित करने हेतु इसे एक स्वायत्त और स्वतंत्र निकाय के रूप में कार्य करने की शक्ति प्रदान की गई है।

48. (B) वृद्धिशील बजट
वृद्धिशील बजटिंग भारत सहित अनेक देशों में प्रचलित प्राचीनतम बजटीय विधि है। इसमें आगामी वर्ष का बजट तैयार करते समय पिछले वर्ष के वास्तविक व्यय को आधार माना जाता है और उसमें मुद्रास्फीति या नवीन आवश्यकताओं हेतु एक निश्चित प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाती है। इस पद्धति का लाभ यह है कि यह सरल और कम समय लेने वाली है। यद्यपि, इसकी आलोचना इसलिए की जाती है क्योंकि यह पुराने और अप्रभावी कार्यक्रमों को बिना किसी गहन समीक्षा के आगे बढ़ाता रहता है, जिससे संसाधनों की बर्बादी होती है।

49. (B) कंट्री क्लब प्रबंधन
रॉबर्ट ब्लेक और जेन माउटन द्वारा विकसित प्रबंधकीय ग्रिड में 'कंट्री क्लब प्रबंधन' शैली उस स्थिति को दर्शाती है जहाँ नेतृत्व कर्मचारियों की भावनाओं और सामाजिक आवश्यकताओं पर अत्यधिक ध्यान देता है। इस शैली में कार्य का वातावरण अत्यंत मैत्रीपूर्ण होता है, किंतु कार्य के लक्ष्यों या उत्पादकता को न्यून प्राथमिकता दी जाती है। नेता का मानना होता है कि यदि लोग प्रसन्न रहेंगे, तो वे बेहतर कार्य करेंगे। यद्यपि, इसमें अक्सर संगठनात्मक उद्देश्यों की उपेक्षा हो जाती है, जिससे उत्पादकता का स्तर निम्न बना रहता है और अनुशासन प्रभावित होता है।

50. (A) केवल 3
लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के अंतर्गत स्थापित लोकपाल एक वैधानिक निकाय है, संवैधानिक नहीं। इसकी संरचना में एक अध्यक्ष और अधिकतम आठ सदस्य होते हैं, जिनमें से आधे न्यायिक सदस्य होने अनिवार्य हैं। प्रधानमंत्री को कुछ सुरक्षा उपायों और गोपनीयता की शर्तों के साथ लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है, अतः वे इससे पूर्णतः बाहर नहीं हैं। लोकपाल को लोक सेवकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने और अभियोग चलाने की व्यापक शक्तियां प्राप्त हैं, जो प्रशासनिक शुचिता हेतु आवश्यक हैं।

51. (C) उत्तरधिकार नियोजन
उत्तराधिकार नियोजन एक रणनीतिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से संगठन भविष्य में रिक्त होने वाले महत्वपूर्ण नेतृत्व पदों हेतु प्रतिभाशाली कर्मचारियों की पहचान और विकास करता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जब भी कोई वरिष्ठ अधिकारी सेवानिवृत्त हो, तो उसका स्थान लेने हेतु योग्य और प्रशिक्षित कर्मी पूर्व से ही तैयार हों। यह प्रक्रिया संगठनात्मक स्थिरता बनाए रखती है और नेतृत्व में किसी भी अंतराल को रोकती है। यह सामान्य भर्ती से भिन्न है क्योंकि यह केवल वर्तमान कर्मियों के विकास और भविष्य की योजना पर केंद्रित है।

52. (D) पिछला प्रशिक्षण और कौशल जो नई परिस्थितियों में अनुकूलन में बाधा डालते हैं।
रॉबर्ट मर्टन के अनुसार 'प्रशिक्षित अक्षमता' वह स्थिति है जहाँ किसी व्यक्ति का पुराना प्रशिक्षण और वर्षों से नियमों का पालन करने का अभ्यास उसे बदलती परिस्थितियों में प्रभावी ढंग से कार्य करने के अयोग्य बना देता है। नौकरशाह नियमों के इतने अभ्यस्त हो जाते हैं कि वे लचीलेपन या नवाचार की आवश्यकता को नहीं समझ पाते। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब किसी विशिष्ट संदर्भ में सीखा गया कौशल दूसरे संदर्भ में बाधक बन जाता है। इससे नौकरशाही में जड़ता आती है और वह आधुनिक समस्याओं के समाधान में विफल होती है।

53. (C) बढ़ती तार्किकता और नियम-आधारित नियंत्रण।
मैक्स वेबर ने 'लौह पिंजरा' वाक्यांश का प्रयोग आधुनिक समाज में बढ़ती तर्कसंगतता और नौकरशाही के दुष्परिणामों को समझाने हेतु किया था। उनका मानना था कि समाज जैसे-जैसे अधिक तार्किक और नियम-बद्ध होता जाएगा, मानवीय स्वतंत्रता और रचनात्मकता न्यून होती जाएगी। नौकरशाही की जकड़न व्यक्ति को नियमों के एक ऐसे जाल में आबद्ध कर देगी जहाँ से निकलना दुष्कर होगा। यह पिंजरा दक्षता तो लाता है, किंतु व्यक्ति की आत्मा और स्वायत्तता को कुचल देता है। यह आधुनिक औद्योगिक युग की एक अनिवार्य किंतु दुखद विशेषता मानी गई है।

54. (B) योग्यता प्रणाली
योग्यता प्रणाली भर्ती की वह विधि है जहाँ चयन का एकमात्र आधार प्रत्याशी की सक्षमता, ज्ञान और कौशल होता है। इसमें लिखित परीक्षा, साक्षात्कार और अन्य परीक्षणों का

NODIA

अनुसार, व्यक्तिगत संबंधों के समावेश से प्रशासन में पक्षपात और भ्रष्टाचार में वृद्धि हो सकती है, जो किसी भी कुशल संगठन की कार्यक्षमता हेतु अत्यंत घातक सिद्ध होता है।

37. (C) विश्लेषणात्मक और समस्या-समाधान क्षमताएं।
मामला अध्ययन विधि प्रशिक्षण की एक ऐसी तकनीक है जहाँ प्रशिक्षुओं को वास्तविक या काल्पनिक जटिल परिस्थितियों का विवरण दिया जाता है। उन्हें उन स्थितियों का विश्लेषण करने और सर्वोत्तम संभव समाधान प्रस्तुत करने हेतु कहा जाता है। यह पद्धति रटने की प्रवृत्ति के बजाय आलोचनात्मक सोच और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता विकसित करती है। लोक सेवकों हेतु यह विधि अत्यंत प्रभावी है क्योंकि यह उन्हें भविष्य में आने वाली प्रशासनिक चुनौतियों का सामना करने हेतु मानसिक रूप से सुदृढ़ और तैयार करती है।

38. (B) पारदर्शिता का अभाव।
सूचना का अधिकार अधिनियम का प्रत्यक्ष प्रहार सरकारी कामकाज में व्याप्त गोपनीयता और अपारदर्शिता पर होता है। इससे पूर्व, अधिकांश प्रशासनिक निर्णय बंद कमरों में लिए जाते थे, जिससे जनता को उनकी प्रक्रिया की जानकारी नहीं मिल पाती थी। इस अधिनियम के माध्यम से अब नागरिक फाइलों और निर्णयों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिससे लोक सेवकों में यह चेतना आती है कि उनके कार्यों की समीक्षा की जा सकती है। यह पारदर्शिता भ्रष्टाचार को कम करने और शासन में नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने में सहायक होती है।

39. (D) उप-सहारा अफ्रीका।
सुशासन की अवधारणा को वैश्विक स्तर पर मान्यता 1989 में विश्व बैंक की उप-सहारा अफ्रीका पर केंद्रित एक रिपोर्ट के पश्चात मिली। इस रिपोर्ट में तर्क दिया गया था कि इन देशों के आर्थिक विकास में विफलता का मुख्य कारण खराब शासन और प्रशासनिक संस्थाओं की दुर्बलता थी। इसके पश्चात, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं ने विकास सहायता को सुशासन की शर्तों, जैसे जवाबदेही, विधि का शासन और पारदर्शिता से जोड़ दिया। इस प्रकार, यह शब्द वैश्विक प्रशासनिक सुधारों का एक अनिवार्य और महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया।

40. (B) P-2, Q-1, R-4, S-3
रॉबर्ट मर्टन ने नौकरशाही में लक्ष्य विस्थापन और प्रशिक्षित अक्षमता की अवधारणा दी, जो नियमों की कठोरता से उत्पन्न होती है। एल्विन गोल्डनर ने नौकरशाही को दंड-केंद्रित और प्रतिनिधि श्रेणियों में विभाजित किया। फिलिप सेल्ज़निक ने अपने अध्ययन में सह-वरण की प्रक्रिया पर बल दिया, जहाँ बाहरी तत्वों को संगठन में सम्मिलित किया जाता है। मिशेल क्रोज़ियर ने नौकरशाही को एक ऐसे संगठन के रूप में देखा जो अपनी त्रुटियों से नहीं सीखता और शक्ति के दुष्चक्र में फंसा रहता है, जिससे सुधार बाधित होता है।

41. (A) नियोजित लक्ष्यों और वास्तविक उपलब्धियों के बीच संतुलन बनाना।
विकास योजना की सबसे जटिल चुनौती कागज़ पर निर्धारित महत्वाकांक्षी लक्ष्यों और जमीनी स्तर पर प्राप्त वास्तविक परिणामों के बीच के अंतर को न्यून करना है। अक्सर अपर्याप्त संसाधन, प्रशासनिक अक्षमता और समन्वय की कमी के कारण योजनाएं अपने निर्धारित समय और बजट में पूर्ण नहीं हो पातीं। इसके लिए निरंतर निगरानी, मूल्यांकन और बदलती परिस्थितियों के अनुसार लचीलापन आवश्यक है। नियोजन की सफलता केवल योजना बनाने में नहीं, बल्कि उसे प्रभावी ढंग से लागू कर अपेक्षित सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन लाने में निहित है।

42. (A) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG)।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एक स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकारी है। इसकी मुख्य जिम्मेदारी संघ और राज्यों के सार्वजनिक व्यय की लेखापरीक्षा करना है। यह सुनिश्चित करता है कि सरकार द्वारा व्यय किया गया धन वास्तव में विधायिका द्वारा स्वीकृत उद्देश्यों हेतु ही उपयोग किया गया है। यह अधिकारी अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, जिसे पश्चात संसद में चर्चा हेतु रखा जाता है। यह संस्था वित्तीय जवाबदेही और भ्रष्टाचार नियंत्रण का एक प्रमुख संवैधानिक स्तंभ है।

43. (D) कोचिंग (मार्गदर्शन)
मार्गदर्शन प्रशिक्षण की एक अत्यंत व्यावहारिक विधि है जहाँ एक वरिष्ठ और अनुभवी अधिकारी अपने कनिष्ठ को प्रत्यक्ष रूप से कार्य के दौरान निर्देश प्रदान करता है। इसमें नया कर्मचारी वास्तविक समस्याओं का सामना करते हुए अपने वरिष्ठ के अनुभव से सीखता है। यह पद्धति निरंतर प्रतिपुष्टि और कौशल सुधार का अवसर प्रदान करती है। प्रशिक्षुता में भी समान प्रक्रिया होती है किंतु वह अधिक औपचारिक और दीर्घकालिक होती है। मार्गदर्शन में मुख्य बल कर्मचारी की कार्यक्षमता को बढ़ाने और उसे विशिष्ट उत्तरदायित्वों हेतु तैयार करने पर होता है।

44. (B) मनोबल एक मनोवैज्ञानिक-शारीरिक स्थिति है जो इच्छाशक्ति को प्रभावित करती है।
मनोबल एक अत्यंत जटिल अवधारणा है जो व्यक्ति की कार्य करने की मानसिक तैयारी और उसके उत्साह से संबद्ध होती है। यह केवल एक मनोवैज्ञानिक स्थिति नहीं है, बल्कि यह कर्मचारी की शारीरिक ऊर्जा और कार्य के प्रति उसकी समग्र इच्छाशक्ति को भी प्रभावित करती है। उच्च मनोबल वाला व्यक्ति प्रतिकूल परिस्थितियों में भी धैर्य और समर्पण के साथ कार्य करता है। यद्यपि यह सामूहिक वातावरण से प्रभावित होता है, किंतु इसका केंद्र व्यक्तिगत अनुभव और संतुष्टि ही होती है। यह सदैव स्थिर नहीं रहता और प्रबंधन के प्रयासों से परिवर्तनीय है।

45. (A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
संगठन में उत्पादकता और मनोबल के बीच सकारात्मक संबंध होता है। मनोबल वास्तव में एक मानसिक स्थिति है जो कर्मचारी की स्वेच्छा से सहयोग करने और लक्ष्यों को प्राप्त करने की तीव्रता को निर्धारित करती है। जब कर्मचारी अपने कार्य से संतुष्ट होते हैं और समूह के उद्देश्यों के प्रति जुड़ाव अनुभव करते हैं, तो उनका कार्य प्रदर्शन स्वाभाविक रूप से श्रेष्ठ हो जाता है। इसलिए, प्रबंधन का सदैव यह प्रयास रहता है कि वह ऐसा

Downloaded from www.pdf.tube

दिया कि नौकरशाही की कठोरता और नियमों पर अत्यधिक निर्भरता के कारण कर्मचारी मूल लक्ष्यों को विस्मृत कर नियमों के पालन को ही अपना अंतिम उद्देश्य मान लेते हैं। इस स्थिति में नियम साधन न रहकर स्वयं साध्य बन जाते हैं। मर्टन के अनुसार, यह प्रवृत्ति संगठन को अकुशल बनाती है क्योंकि यह बदलती परिस्थितियों के प्रति अनुकूलन की क्षमता को समाप्त कर देती है और प्रशासनिक जड़ता को बढ़ावा देती है।

64. (B) तटस्थता
तटस्थता का सिद्धांत यह अपेक्षा करता है कि एक लोक सेवक किसी भी राजनीतिक विचारधारा या दल के प्रति पक्षपाती हुए बिना केवल तथ्यों, कानूनों और जनहित के आधार पर कार्य करे। इसका अर्थ है कि सरकार परिवर्तित होने पर भी लोक सेवक की निष्ठा केवल संविधान और कानून के प्रति होनी चाहिए। तटस्थ अधिकारी मंत्री को ईमानदार और निर्भीक सलाह प्रदान करता है, भले ही वह सलाह मंत्री की राजनीतिक प्राथमिकताओं के विपरीत हो। यह सिद्धांत सिविल सेवा की व्यावसायिकता और लोकतांत्रिक स्थिरता को बनाए रखने हेतु अनिवार्य है।

65. (B) सरकार वास्तव में क्या कर रही है, इसके बारे में जानकारी न देने के लिए।
मद-वार बजट मुख्य रूप से व्यय की जाने वाली वस्तुओं की सूची और उनके लिए आवंटित धनराशि पर केंद्रित होता है। इसकी सबसे बड़ी आलोचना यह है कि यह केवल व्यय के वित्तीय पक्ष को दर्शाता है, किंतु यह स्पष्ट नहीं करता कि उस व्यय के माध्यम से कौन से विशिष्ट सामाजिक या आर्थिक लक्ष्य प्राप्त किए जा रहे हैं। इसमें परिणामों और प्रदर्शन की उपेक्षा की जाती है, जिससे यह समझना कठिन हो जाता है कि सार्वजनिक धन का उपयोग कितना प्रभावी रहा। यह बजट नियंत्रण का साधन तो है, किंतु प्रबंधन का नहीं।

66. (A) एक कठोर, नियम-बद्ध संरचना जो नवाचार को रोकती है।
विकास प्रशासन का मुख्य उद्देश्य तीव्र सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन लाना है, जिसके लिए लचीलेपन, नवाचार और त्वरित निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। इसके विपरीत, पारंपरिक नौकरशाही अपनी कठोर पदानुक्रमित संरचना और नियमों के शाब्दिक पालन हेतु जानी जाती है। यह नियम-बद्धता अक्सर रचनात्मक समाधानों को हतोत्साहित करती है और परिवर्तन की प्रक्रिया को मंद कर देती है। विकास की चुनौतियों का सामना करने हेतु नौकरशाही को परिणाम-उन्मुख और नागरिक-केंद्रित होने की आवश्यकता है, जो उसकी मौजूदा संरचनात्मक सीमाओं के कारण एक बड़ी चुनौती है।

67. (C) 48 घंटे
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 नागरिकों के अधिकारों के प्रति अत्यंत संवेदनशील है। सामान्य प्रकरणों में सूचना प्रदान करने की अवधि 30 दिन निर्धारित है, किंतु यदि मांगी गई जानकारी किसी व्यक्ति के जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़ी है, तो अधिनियम के अनुसार जन सूचना अधिकारी को इसे 48 घंटों के भीतर उपलब्ध कराना अनिवार्य है। यह प्रावधान मानवीय गरिमा और अधिकारों की रक्षा हेतु किया गया है ताकि किसी आपातकालीन स्थिति में प्रशासनिक विलंब के कारण किसी व्यक्ति के जीवन को कोई क्षति न पहुँचे।

68. (D) स्वीडन
ओम्बुड्समैन की अवधारणा का उदय सर्वप्रथम 1809 में स्वीडन में हुआ था। इसका उद्देश्य नागरिकों की शिकायतों को सुनना और प्रशासन द्वारा सत्ता के दुरुपयोग की जांच करना था। स्वीडन की सफलता के पश्चात, इस मॉडल को विश्व भर के अनेक देशों ने अपनाया, जिसे भारत में लोकपाल और लोकायुक्त के रूप में जाना जाता है। यह संस्था कार्यपालिका से पूर्णतः स्वतंत्र होती है और भ्रष्टाचार तथा कुप्रशासन के विरुद्ध जनता हेतु एक सुरक्षा कवच का कार्य करती है। यह लोकतांत्रिक जवाबदेही सुनिश्चित करने का एक वैश्विक मानक बन गया है।

69. (B) कार्य और वातावरण के प्रति मानसिक और भावनात्मक दृष्टिकोण।
कर्मचारी मनोबल एक अमूर्त अवधारणा है जो कार्यस्थल पर व्यक्ति की मानसिक अवस्था, उत्साह और संतुष्टि के स्तर को व्यक्त करती है। यह कर्मचारी के आत्मविश्वास और संगठन के उद्देश्यों के प्रति उसके भावनात्मक जुड़ाव का प्रतिबिंब है। उच्च मनोबल से कर्मचारियों में सहयोग की भावना बढ़ती है और वे स्वेच्छा से अधिक परिश्रम करते हैं। इसके विपरीत, निम्न मनोबल कार्य के प्रति उदासीनता और अनुशासनहीनता की ओर ले जाता है। मनोबल केवल भौतिक लाभों से नहीं, बल्कि सम्मान और अच्छे मानवीय संबंधों से भी सर्वाधिक प्रभावित होता है।

70. (B) P-3, Q-4, R-1, S-2
भर्ती का मुख्य कार्य संगठन की रिक्तियों हेतु योग्य और कुशल उम्मीदवारों को खोजकर उन्हें आवेदन के लिए आकर्षित करना है। प्रशिक्षण का उद्देश्य चयनित कर्मियों के ज्ञान और व्यावसायिक कौशल में वृद्धि करना है ताकि वे अपने उत्तरदायित्वों को बेहतर ढंग से निभा सकें। पदोन्नति के माध्यम से कर्मचारियों को उनके श्रेष्ठ प्रदर्शन के पुरस्कार स्वरूप उच्च पदों और जिम्मेदारियों पर नियुक्त किया जाता है। अनुशासन एक ऐसी व्यवस्था है जो कर्मचारियों के अवांछनीय व्यवहार में सुधार लाने और संगठन के नियमों का पालन सुनिश्चित करने पर केंद्रित है।

71. (D) परिस्थिति और अनुयायियों की परिपक्वता पर पर निर्भर करती है।
नेतृत्व का स्थितिजन्य सिद्धांत यह तर्क देता है कि कोई भी एक नेतृत्व शैली प्रत्येक स्थिति में सर्वोत्तम नहीं हो सकती। एक प्रभावी नेता वह है जो परिस्थिति की मांगों और अपने अनुयायियों की योग्यता तथा परिपक्वता के स्तर के अनुसार अपनी शैली को परिवर्तित कर लेता है। उदाहरण के लिए, अनुभवी कर्मचारियों के साथ सहयोगात्मक शैली और नवीन कर्मचारियों के साथ निर्देशात्मक शैली अधिक प्रभावी होती है। यह सिद्धांत मानता है कि नेता को लचीला होना चाहिए और उसे अपने व्यवहार को वातावरण की आवश्यकताओं के अनुकूल ढालना चाहिए।

NODIA

के तीव्र सामाजिक-आर्थिक उत्थान हेतु राज्य को संसाधनों का मुख्य प्रबंधक और दिशा-निर्देशक होना चाहिए। योजना आयोग की स्थापना और पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत इसी दिशा में उठाए गए कदम थे। राज्य का लक्ष्य केवल विकास करना ही नहीं, बल्कि न्यायसंगत वितरण और गरीबी उन्मूलन भी था। इस मॉडल में सार्वजनिक क्षेत्र को रणनीतिक महत्व प्रदान किया गया और निजी क्षेत्र को राज्य निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार कार्य करना था।

90. (A) सुनना
लेखापरीक्षा शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द 'ऑडिरे' से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है 'सुनना'। प्राचीन काल में, जब खातों का रखरखाव मौखिक रूप से होता था, तो एक अधिकृत परीक्षक हिसाब-किताब के विवरणों को सुनता था और उनकी सत्यता की पुष्टि करता था। समय के साथ, यह प्रक्रिया जटिल लिखित लेखांकन और सूक्ष्म जाँच में परिवर्तित हो गई, किंतु इसका मूल भाव वही रहा। आज के संदर्भ में, इसका अर्थ वित्तीय दस्तावेजों और लेनदेन की सूक्ष्मता से जाँच करना और उनके विधिक अनुपालन को सत्यापित करना है।

91. (D) उपलब्ध सूचना के साथ नियमों का पालन करते हुए निर्णय लिए जाते हैं।
प्रशासन में पारदर्शिता का अर्थ है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया और उसके आधार जनता हेतु स्पष्ट और सुलभ होने चाहिए। इसका तात्पर्य है कि लोक सेवक नियमों और स्थापित प्रक्रियाओं के अनुसार ही कार्य करें और उनके कार्यों की निगरानी समाज द्वारा की जा सके। पारदर्शिता न केवल भ्रष्टाचार को रोकने में सहायता करती है, बल्कि यह सरकार की विश्वसनीयता को भी बढ़ाती है। जब नागरिक यह जान पाते हैं कि कोई निर्णय क्यों और कैसे लिया गया है, तो वे स्वयं को शासन प्रक्रिया का हिस्सा अनुभव करते हैं, जो सुशासन का आधार है।

92. (B) (A) और (D) दोनों सही हैं।
लोकपाल एक बहु-सदस्यीय संस्था है जिसकी संरचना में विविधता और विशेषज्ञता को महत्व दिया गया है। अधिनियम के अनुसार, इसके कुल सदस्यों में से कम से कम 50% सदस्य न्यायिक पृष्ठभूमि से होने चाहिए ताकि विधिक मामलों की गहन समझ बनी रहे। इसके अतिरिक्त, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने हेतु यह प्रावधान भी है कि कम से कम 50% सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के वर्ग से हों। यह संतुलित संरचना लोकपाल को अधिक समावेशी, निष्पक्ष और प्रभावी बनाती है।

93. (A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।
सीधी भर्ती और आंतरिक पदोन्नति दोनों के अपने लाभ और सीमाएं हैं। सीधी भर्ती संगठन में नवीन प्रतिभाओं और नए विचारों का संचार करती है, जिससे प्रशासनिक संरचना आधुनिक बनी रहती है। वहीं दूसरी ओर, केवल आंतरिक पदोन्नति पर निर्भर रहने से 'अंतर्प्रजनन' का भय रहता है, जहाँ कर्मचारी केवल पुरानी और पारंपरिक पद्धतियों का ही अनुसरण करते रहते हैं, जिससे नवाचार की कमी हो जाती है। एक कुशल कार्मिक प्रणाली वही है जो इन दोनों विधियों के बीच उचित संतुलन बनाकर संगठन की गतिशीलता और कर्मचारियों की आकांक्षाओं को बनाए रखती है।

94. (D) लूट पद्धति (स्पॉइल्स सिस्टम)
एफ.एम. मार्क्स द्वारा वर्णित संरक्षण नौकरशाही वास्तव में अमेरिका की प्रसिद्ध 'लूट पद्धति' का ही एक रूप है। इस व्यवस्था में सरकारी पदों पर नियुक्तियां उम्मीदवार की योग्यता के बजाय सत्ताधारी दल के प्रति उसकी वफादारी और राजनीतिक संबंधों के आधार पर की जाती हैं। चुनाव जीतने के पश्चात, नेता अपने समर्थकों को पुरस्कृत करने हेतु उन्हें महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर आसीन कर देते हैं। यद्यपि यह व्यवस्था राजनीतिक नियंत्रण को सुदृढ़ करती है, किंतु यह प्रशासन की व्यावसायिकता, तटस्थता और दीर्घकालिक कार्यकुशलता को गंभीर रूप से क्षति पहुँचाती है।

95. (A) प्रेषक द्वारा किसी विचार को प्रेषण योग्य संदेश में बदलने का कार्य।
संचार प्रक्रिया में 'संकेतीकरण' वह प्रारंभिक चरण है जहाँ प्रेषक अपने मस्तिष्क के विचारों, भावनाओं या सूचनाओं को प्रतीकों, शब्दों या चित्रों के रूप में ढालता है। इसका उद्देश्य विचार को एक ऐसे स्वरूप में लाना है जिसे किसी माध्यम द्वारा प्राप्तकर्ता तक प्रेषित किया जा सके। संकेतीकरण की प्रभावशीलता प्रेषक की भाषा क्षमता और परिस्थितियों की समझ पर निर्भर करती है। यदि संकेतीकरण स्पष्ट और सरल हो, तो प्राप्तकर्ता हेतु संदेश को समझना सुगम हो जाता है, जिससे संचार के सफल होने की संभावना अत्यधिक बढ़ जाती है।

96. (B) पदोन्नति
सरकारी सेवा में अनुशासन बनाए रखने हेतु विभिन्न दंडों का प्रावधान है। परिनिंदा, वेतन वृद्धि रोकना और सेवा से बर्खास्तगी अनुशासनात्मक कार्यवाही के पश्चात दिए जाने वाले दंडात्मक उपाय हैं। इसके विपरीत, पदोन्नति एक सकारात्मक कार्मिक कार्य है जो कर्मचारी के श्रेष्ठ प्रदर्शन और वरिष्ठता हेतु पुरस्कार स्वरूप प्रदान किया जाता है। पदोन्नति से कर्मचारी का वेतन, प्रतिष्ठा और जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, जबकि दंड का उद्देश्य अवांछनीय आचरण को सुधारना या रोकना होता है। अतः पदोन्नति को किसी भी स्थिति में दंड की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता।

97. (B) कार्य परिवर्तन (जॉब रोटेशन)
कार्य परिवर्तन प्रशिक्षण की एक ऐसी विधि है जिसमें कर्मचारियों को नियमित अंतराल पर संगठन के विभिन्न विभागों या भिन्न-भिन्न कार्यों में स्थानांतरित किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य कर्मचारी को संगठन के कामकाज का व्यापक अनुभव प्रदान करना और उसे बहु-कौशल युक्त बनाना है। इससे न केवल कार्य में एकरसता न्यून होती है, बल्कि कर्मचारी भविष्य में उच्च प्रबंधन पदों हेतु भी तैयार होता है क्योंकि उसे विभिन्न क्षेत्रों की सूक्ष्म जानकारी प्राप्त हो जाती है। यह पद्धति अंतर-विभागीय समन्वय को भी बेहतर बनाने में अत्यंत सहायक सिद्ध होती है।

Click Here to Buy book on Amazon

प्रभावशीलता को प्रत्यक्ष प्रभावित करती है। एक सफल नेता वही है जो जटिल परिस्थितियों में समय पर सटीक निर्णय लेने का कौशल रखता हो।

81. (B) एक ही पदानुक्रमित स्तर पर कार्यरत कर्मचारी।
क्षैतिज संचार संगठन में एक ही समान स्तर पर कार्य करने वाले विभिन्न विभागों या इकाइयों के बीच होता है। उदाहरण हेतु, जब वित्त विभाग का प्रबंधक उत्पादन विभाग के प्रबंधक से संवाद करता है, तो यह क्षैतिज संचार है। इसका मुख्य उद्देश्य विभागों के बीच समन्वय स्थापित करना, सूचनाओं का आदान-प्रदान करना और समस्याओं का मिलकर समाधान करना है। यह पदानुक्रम की जटिलताओं को कम करता है और संगठन में कार्य की गति को बढ़ाता है, जिससे विभिन्न इकाइयों के बीच बेहतर समझ और सहयोग निरंतर विकसित होता रहता है।

82. (A) मानकीकृत प्रक्रियाएं और लचीलेपन की आवश्यकता।
विकास प्रशासन को प्रायः एक विरोधाभास का सामना करना पड़ता है जहाँ एक ओर नौकरशाही को निष्पक्षता हेतु स्थापित नियमों और मानकीकृत प्रक्रियाओं का पालन करना होता है, तो दूसरी ओर विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु नवाचार और लचीलेपन की आवश्यकता होती है। कठोर नियम अक्सर स्थानीय परिस्थितियों और बदलती आवश्यकताओं के प्रति असंवेदनशील होते हैं, जिससे जनकल्याणकारी योजनाओं की गति मंद हो जाती है। इस संघर्ष का समाधान एक ऐसी संतुलित प्रशासनिक संस्कृति विकसित करने में है जो नियमों की मर्यादा के भीतर रचनात्मकता को उचित स्थान दे सके।

83. (C) एक लिपिक फाइल को शीघ्र बढ़ाने के लिए रिश्वत की मांग कर रहा है।
सार्वजनिक प्रशासन में भ्रष्टाचार का अर्थ है अपने आधिकारिक पद और शक्ति का व्यक्तिगत लाभ हेतु दुरुपयोग करना। जब कोई कर्मचारी किसी ऐसे कार्य हेतु अवैध धन या उपहार की मांग करता है जो उसका विधिक कर्तव्य है, तो यह भ्रष्टाचार का एक स्पष्ट उदाहरण है। यह न केवल अनैतिक है बल्कि न्याय और समानता के सिद्धांतों के भी विरुद्ध है। रिश्वतखोरी से प्रशासनिक दक्षता प्रभावित होती है और नागरिकों का सरकार पर से विश्वास न्यून हो जाता है। भ्रष्टाचार को रोकने हेतु कठोर कानून और पारदर्शी प्रक्रियाओं की नितांत आवश्यकता होती है।

84. (D) महाराष्ट्र
भारत में लोकायुक्त संस्था की स्थापना करने वाला प्रथम राज्य महाराष्ट्र था, जिसने 1971 में इस संबंध में कानून पारित किया था। लोकायुक्त राज्य स्तर पर भ्रष्टाचार और कुप्रशासन के विरुद्ध एक स्वतंत्र प्रहरी के रुप में कार्य करता है। यद्यपि राजस्थान, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों ने भी पश्चात में इस संस्था को अपनाया, किंतु महाराष्ट्र ने इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभाई। इस संस्था का उद्देश्य मंत्रियों और लोक सेवकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की निष्पक्ष जांच करना और प्रशासन में शुचिता बनाए रखना है, जो सुशासन का अनिवार्य अंग है।

85. (A) 2, 1, 4, 3
बजट के स्वरूपों का विकास क्रमिक रूप से हुआ है। सर्वप्रथम मद-वार बजट आया, जिसका मुख्य उद्देश्य व्यय पर नियंत्रण रखना था। इसके पश्चात निष्पादन बजट का विकास हुआ, जिसने कार्यों और परिणामों पर बल दिया। 1960 के दशक में नियोजन, कार्यक्रम निर्धारण, बजट प्रणाली की शुरुआत हुई, जो दीर्घकालिक लक्ष्यों पर आधारित थी। अंत में, 1970 के दशक में शून्य-आधारित बजटिंग की अवधारणा विकसित हुई, जिसमें प्रत्येक वर्ष बजट का नए सिरे से औचित्य सिद्ध करने पर बल दिया गया। यह विकास बढ़ती वित्तीय जटिलताओं के प्रति प्रशासनिक अनुक्रिया है।

86. (B) सकारात्मक कार्य वातावरण और प्रोत्साहन प्रदान करना।
कर्मचारियों के मनोबल में सुधार हेतु सबसे प्रभावी तरीका एक ऐसा वातावरण तैयार करना है जहाँ उन्हें सम्मान और सुरक्षा का अनुभव हो। सकारात्मक कार्य वातावरण में खुला संचार, अच्छे मानवीय संबंध और कार्यों की सराहना सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त, वित्तीय और गैर-वित्तीय प्रोत्साहन जैसे बोनस, पदोन्नति के अवसर और मान्यता, कर्मचारियों को श्रेष्ठ प्रदर्शन हेतु प्रेरित करते हैं। कठोर नियम या दंड देने से तात्कालिक अनुशासन तो आ सकता है, किंतु यह दीर्घकालिक मनोबल और उत्पादकता हेतु अत्यंत हानिकारक सिद्ध होता है।

87. (D) औपचारिक और अनौपचारिक सह-वरण (को-ऑप्टेशन)।
फिलिप सेल्ज़निक ने टेनेसी वैली अथॉरिटी के अपने प्रसिद्ध अध्ययन में 'सह-वरण' की अवधारणा विकसित की थी। उन्होंने बताया कि कैसे एक संगठन अपने अस्तित्व को बनाए रखने और बाहरी विरोध को कम करने हेतु स्थानीय समुदायों या विरोधी समूहों के नेताओं को अपनी निर्णय लेने वाली संरचना में सम्मिलित कर लेता है। यह प्रक्रिया औपचारिक भी हो सकती है और अनौपचारिक भी। सेल्ज़निक ने यह स्पष्ट किया कि इस प्रक्रिया के दौरान कभी-कभी संगठन के मूल लक्ष्य परिवर्तित हो जाते हैं, क्योंकि उसे बाहरी तत्वों की मांगों के साथ समझौता करना पड़ता है।

88. (A) राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका के संबंध।
मंत्री और लोक सेवक के बीच का संबंध वास्तव में राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका के समन्वय का प्रतिनिधित्व करता है। निर्वाचित मंत्री राजनीतिक निर्णयों और नीति निर्माण हेतु जिम्मेदार होते हैं, जबकि लोक सेवक अपनी विशेषज्ञता के माध्यम से उन्हें क्रियान्वित करते हैं। लोक सेवक स्थायी होते हैं और सरकार परिवर्तित होने पर भी पद पर बने रहते हैं, जिससे प्रशासनिक निरंतरता बनी रहती है। इन दोनों अंगों के बीच सुचारु संबंध और स्पष्ट भूमिकाएं ही एक सफल लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था हेतु अनिवार्य आधार प्रदान करती हैं।

89. (C) आर्थिक विकास के मार्गदर्शन में राज्य की केंद्रीय भूमिका है।
स्वतंत्रता के पश्चात भारत ने विकास योजना का जो मॉडल अपनाया, वह इस विश्वास पर आधारित था कि एक पिछड़े देश

Downloaded from www.pdf.tube

उपयोग यह सुनिश्चित करने हेतु किया जाता है कि पद हेतु सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार का ही चयन हो। यह प्रणाली निष्पक्षता और तटस्थता को बढ़ावा देती है और 'लूट पद्धति' के विपरीत है जहाँ नियुक्तियां राजनीतिक संबंधों पर आधारित होती हैं। यह आधुनिक सिविल सेवा का आधार है जो प्रशासन में व्यावसायिकता और कार्यकुशलता सुनिश्चित करती है।

55. (C) कथन I सत्य है लेकिन कथन II असत्य है।
नेतृत्व का अर्थ है अनुयायियों को साझा उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु स्वेच्छा से कार्य करने के लिए प्रभावित करना। यद्यपि प्रबंधन और नेतृत्व एक-दूसरे से आबद्ध हैं, किंतु वे पूर्णतः समान नहीं हैं। एक प्रबंधक मुख्य रूप से योजना, संगठन और नियंत्रण जैसे कार्यों पर ध्यान केंद्रित करता है और अपनी औपचारिक शक्ति का उपयोग करता है। एक नेता वह है जो लोगों को प्रेरित करता है और उनकी मानसिकता में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। इसलिए, सभी प्रबंधक अनिवार्य रूप से अच्छे नेता नहीं होते, और कुछ प्रभावी नेता औपचारिक पद के बिना भी हो सकते हैं।

56. (A) कोई भी कारक जो संदेश को विकृत करता है या उसमें हस्तक्षेप करता है।
संचार प्रक्रिया में 'शोर' का तात्पर्य किसी भी ऐसे व्यवधान से है जो प्रेषक द्वारा भेजे गए संदेश को प्राप्तकर्ता तक वास्तविक रूप में पहुँचने से रोकता है। यह शोर भौतिक हो सकता है, जैसे तकनीकी खराबी, या मनोवैज्ञानिक भी हो सकता है, जैसे पूर्वग्रह या असावधानी। इसके अतिरिक्त, भाषा संबंधी अस्पष्टता भी शोर का एक रूप है। शोर के कारण संदेश का मूल अर्थ परिवर्तित हो सकता है या वह अधूरा रह सकता है, जिससे संगठन में गलतफहमी और कार्य में बाधा उत्पन्न होती है।

57. (C) सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP)।
उदारीकरण के पश्चात भारतीय प्रशासन ने निजी क्षेत्र के संसाधनों और विशेषज्ञता का लाभ प्राप्त करने हेतु सार्वजनिक-निजी भागीदारी प्रारूप को प्राथमिकता दी है। इसका उद्देश्य बुनियादी ढांचे के विकास और सार्वजनिक सेवाओं के वितरण में दक्षता और नवीनता लाना है। इस प्रारूप के अंतर्गत सरकार और निजी कंपनियां मिलकर परियोजनाओं का वित्तपोषण और संचालन करती हैं। यह राज्य के पारंपरिक एकाधिकार को समाप्त करने और एक सहयोगी अर्थव्यवस्था के निर्माण की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे करदाताओं के धन का अधिक प्रभावी उपयोग संभव होता है।

58. (A) मद-वार बजट - व्यय की मदों पर नियंत्रण पर केंद्रित
मद-वार बजट पारंपरिक बजटीय प्रणाली है जहाँ मुख्य बल इस बात पर होता है कि धन किन वस्तुओं पर व्यय किया जा रहा है, जैसे वेतन या स्टेशनरी। इसका प्राथमिक उद्देश्य विधायी नियंत्रण सुनिश्चित करना और धन के दुरुपयोग को रोकना है। इसमें प्रत्येक व्यय हेतु एक सीमा निर्धारित होती है जिसे पार करना कठिन होता है। यद्यपि यह वित्तीय शुचिता बनाए रखने में सहायक है, किंतु यह इस बात की जानकारी नहीं देता कि उस व्यय से वास्तव में समाज को क्या लाभ या परिणाम प्राप्त हुए हैं।

59. (D) लोकपाल राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करता है जबकि लोकायुक्त राज्य स्तर पर।
लोकपाल और लोकायुक्त दोनों ही भ्रष्टाचार विरोधी संस्थाएं हैं, किंतु उनके अधिकार क्षेत्र के स्तर भिन्न-भिन्न हैं। लोकपाल केंद्र सरकार के मंत्रियों, संसद सदस्यों और केंद्रीय कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की जांच करने वाला राष्ट्रीय निकाय है। इसके विपरीत, लोकायुक्त राज्य स्तर पर कार्य करता है और राज्य सरकार के लोक सेवकों और राजनीतिक पदाधिकारियों की जांच करता है। भारत में महाराष्ट्र प्रथम राज्य था जिसने लोकायुक्त संस्था की स्थापना की थी। दोनों संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता और जवाबदेही लाना है।

60. (B) गोपनीयता
सुशासन के स्तंभों में भागीदारी, जवाबदेही, पारदर्शिता और विधि का शासन सम्मिलित हैं। अंतरराष्ट्रीय संगठनों के अनुसार, सुशासन वह है जहाँ सरकार अपने कार्यों और निर्णयों को जनता के समक्ष स्पष्ट रखे। इसके विपरीत, गोपनीयता सुशासन की अवधारणा के विरुद्ध है क्योंकि यह भ्रष्टाचार और मनमानी को बढ़ावा देती है। जब प्रशासन गोपनीय होता है, तो नागरिक अपने अधिकारों का पूर्ण प्रयोग नहीं कर पाते और न ही सरकार को जवाबदेह बना पाते हैं। सुशासन में सूचना के खुलेपन को लोक कल्याण हेतु अनिवार्य माना जाता है।

61. (C) अनौपचारिक संचार माध्यम।
'ग्रेपवाइन' या जनश्रुति किसी संगठन के भीतर अनौपचारिक संचार नेटवर्क को कहा जाता है। यह औपचारिक पदानुक्रम के नियमों का पालन नहीं करता और सामाजिक संबंधों के आधार पर तीव्रता से प्रसारित होता है। यद्यपि इसमें सूचनाओं के विकृत होने या अफवाहों के फैलने का जोखिम होता है, किंतु यह प्रबंधन को कर्मचारियों की वास्तविक भावनाओं और प्रतिक्रियाओं को समझने में सहायता करता है। यह अक्सर औपचारिक माध्यमों की तुलना में बहुत अधिक तीव्र होता है और अनौपचारिक समूहों के बीच सूचना आदान-प्रदान का प्रमुख स्रोत है।

62. (D) कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों के आधार पर पदों का समूहन करना।
पद वर्गीकरण कार्मिक प्रशासन की एक वैज्ञानिक पद्धति है जहाँ पदों को उनके कार्य की प्रकृति, कठिनाई के स्तर और आवश्यक कौशल के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य 'समान कार्य हेतु समान वेतन' सुनिश्चित करना है। यह व्यक्ति के बजाय पद पर ध्यान केंद्रित करता है, जिससे भर्ती, प्रशिक्षण और वेतन निर्धारण में वस्तुनिष्ठता आती है। यह प्रणाली पदानुक्रम को तार्किक बनाती है और कर्मचारियों को उनके उत्तरदायित्वों के प्रति स्पष्टता प्रदान करती है, जो किसी भी बड़े संगठन के प्रभावी प्रबंधन हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है।

63. (A) रॉबर्ट के. मर्टन
रॉबर्ट के. मर्टन ने नौकरशाही का समाजशास्त्रीय विश्लेषण करते हुए 'लक्ष्य विस्थापन' की अवधारणा प्रस्तुत की थी। उन्होंने तर्क

NODIA

98. (A) विकासात्मक/नियंत्रणकारी से नियामक भूमिका की ओर बदलाव।
उदारीकरण के आगमन से भारतीय प्रशासन की भूमिका में मौलिक परिवर्तन आया है। पूर्व में सरकार स्वयं उद्योगों का संचालन और कठोर नियंत्रण करती थी, किंतु अब वह एक 'नियामक' की भूमिका में आ गई है। इसका अर्थ है कि प्रशासन अब बाजार की प्रतिस्पर्धा को सुगम बनाने, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने और निवेश हेतु अनुकूल वातावरण तैयार करने पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है। विभिन्न नियामक निकायों का गठन इसी बदलाव का प्रतीक है। यह नवीन भूमिका नौकरशाही से अधिक व्यावसायिकता, विशेषज्ञता और बाजार की समझ की अपेक्षा करती है।

99. (C) कर्मचारी के आचरण की एक औपचारिक और दर्ज की गई अस्वीकृति।
परिनिंदा सरकारी सेवा में एक 'लघु दंड' के रूप में जानी जाती है। यह कर्मचारी के सेवा अभिलेख में दर्ज की जाने वाली एक आधिकारिक चेतावनी है जो उसके द्वारा किए गए किसी विशिष्ट कदाचार या लापरवाही के विरुद्ध जारी की जाती है। यद्यपि इसमें कर्मचारी के पद या वेतन में तत्काल कोई परिवर्तन नहीं होता, किंतु यह उसके भविष्य की पदोन्नति और प्रदर्शन मूल्यांकन को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है। इसका उद्देश्य कर्मचारी को सचेत करना है कि उसका व्यवहार मानकों के अनुरूप नहीं है और उसे सुधार की नितांत आवश्यकता है।

100. (B) P-3, Q-4, R-1, S-2
लोकपाल की मुख्य भूमिका उच्च पदों पर आसीन लोक सेवकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की निष्पक्ष जांच करना है। केंद्रीय सतर्कता आयोग विभिन्न सरकारी विभागों में सतर्कता प्रशासन का पर्यवेक्षण करता है और अधिकारियों को आवश्यक परामर्श देता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की संवैधानिक जिम्मेदारी सरकारी प्राप्तियों और व्यय के खातों की सूक्ष्मता से लेखापरीक्षा करना है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो एक प्रमुख जांच एजेंसी है जो भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराधों और अन्य महत्वपूर्ण आपराधिक मामलों की गहराई से जांच करने हेतु विधिक रूप से अधिकृत है।

101. (C) कानून स्पष्ट, स्थिर और समान रूप से लागू हैं।
सुशासन में 'विधि का शासन' इस सिद्धांत पर आधारित है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, कानून से ऊपर नहीं है। इसका अर्थ है कि प्रशासन की शक्तियां मनमानी नहीं हो सकतीं और उन्हें केवल पूर्व-निर्धारित स्पष्ट नियमों के अनुसार ही प्रयोग किया जाना चाहिए। विधि का शासन समानता, न्याय और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। जब कानून स्थिर और पारदर्शी होते हैं, तो समाज में व्यवस्था बनी रहती है और लोग प्रशासनिक निर्णयों के प्रति विश्वास और पूर्वानुमान का अनुभव करते हैं।

102. (B) लालफीताशाही
लालफीताशाही नौकरशाही का एक प्रमुख दुष्कार्य है जो नियमों और औपचारिकताओं के प्रति अत्यधिक लगाव को दर्शाता है। इसमें फाइलों के निपटान में अनावश्यक विलंब होता है क्योंकि अधिकारी लकीर के फकीर बनकर प्रक्रिया को परिणाम से अधिक महत्व देने लगते हैं। यह स्थिति प्रशासनिक दक्षता को कम करती है और आम जनता हेतु उत्पीड़न का कारण बनती है। यद्यपि पदानुक्रम और तार्किकता नौकरशाही के सकारात्मक अंग हैं, किंतु जब वे अत्यधिक और अनावश्यक बाधाएं बन जाते हैं, तो वे लालफीताशाही का रूप ले लेते हैं जो सुशासन के लक्ष्यों को बाधित करता है।

103. (D) सरकार और कर्मचारियों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध।
संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र की स्थापना भारत में केंद्र सरकार और उसके कर्मचारियों के बीच संवाद के सेतु के रूप में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य वेतन, सेवा शर्तों और कल्याणकारी विषयों पर आपसी बातचीत के माध्यम से विवादों को सुलझाना है। यह मंच कर्मचारियों को अपनी समस्याएं प्रस्तुत करने का अवसर देता है और हड़ताल जैसी स्थितियों को टालने में सहायता करता है। इस तंत्र की सफलता प्रशासन में शांति बनाए रखने और एक सहयोगात्मक कार्य संस्कृति को बढ़ावा देने में निहित है, जिससे अंततः सरकारी कार्यक्षमता में वृद्धि होती है।

104. (A) मद-वार बजट (लाइन-आइटम बजट)
मद-वार बजट प्रणाली में समस्त ध्यान केवल व्यय की गई राशि और क्रय की गई वस्तुओं, जैसे स्टेशनरी, उपस्कर या कर्मचारियों के वेतन पर होता है। यह बजट सरकार के 'आगत' पर तो नियंत्रण रखता है, किंतु यह स्पष्ट नहीं करता कि इन व्ययों के माध्यम से समाज को क्या वास्तविक लाभ प्राप्त हुआ। इसमें केवल वित्तीय शुचिता और नियमों के पालन को ही सफलता का मानदंड माना जाता है। चूँकि यह परिणामों की उपेक्षा करता है, इसलिए इसे आधुनिक प्रबंधन की दृष्टि से अपर्याप्त माना जाता है, जो केवल बजट की मदों तक सीमित रहता है।

105. (A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
विकास प्रशासन पारंपरिक प्रशासन से भिन्न है क्योंकि इसका मुख्य सरोकार केवल व्यवस्था बनाए रखना नहीं, बल्कि समाज में व्यापक सकारात्मक परिवर्तन लाना है। विकास प्रशासन को एक ऐसी गतिशील नौकरशाही की आवश्यकता होती है जो केवल नियमों में न उलझकर परिणामों को प्राथमिकता प्रदान करे। यह दृष्टिकोण पूर्णतः नागरिक-केंद्रित होता है और विकास लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से प्राप्त करने पर बल देता है। इसलिए, विकासशील देशों में नौकरशाही को अपनी मानसिकता परिवर्तित कर एक सक्रिय परिवर्तन अभिकर्ता की भूमिका निभानी पड़ती है।

106. (A) क्षमताओं और कार्य की आवश्यकताओं के बीच के अंतराल को पाटना।
प्रशिक्षण का प्राथमिक उद्देश्य लोक सेवकों के वर्तमान कौशल स्तर और उनके पद हेतु आवश्यक दक्षता के बीच के अंतराल को न्यून करना है। जैसे-जैसे तकनीक और शासन की चुनौतियाँ परिवर्तित होती हैं, कर्मचारियों को नवीन ज्ञान और दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। प्रशिक्षण उन्हें इन परिवर्तनों के अनुकूल बनाता है, जिससे उनकी कार्यक्षमता और उत्पादकता

Click Here to Buy book on Amazon

72. (A) खेने (रोइंग) के बजाय दिशा देना (स्टीयरिंग)।
उदारीकरण के पश्चात राज्य की भूमिका में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। 'खेने' का अर्थ है सरकार द्वारा स्वयं वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना, जबकि 'दिशा देना' का अर्थ है निजी क्षेत्र को अवसर प्रदान करना और उनके कार्यों का नियमन करना। आधुनिक युग में सरकार अब मुख्य रूप से नीतियां बनाने और नियामक निकायों के माध्यम से निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। यह बदलाव राज्य को अपनी प्रशासनिक क्षमता का उपयोग व्यापक जनकल्याण और रणनीतिक क्षेत्रों के प्रबंधन में करने की अनुमति प्रदान करता है।

73. (C) जवाबदेही और पारदर्शिता।
सामाजिक लेखापरीक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी सरकारी योजना या कार्यक्रम के वास्तविक लाभार्थियों और स्थानीय समुदाय द्वारा उसके क्रियान्वयन का मूल्यांकन किया जाता है। यह पारंपरिक वित्तीय लेखापरीक्षा से भिन्न है क्योंकि इसमें धन के व्यय के साथ-साथ उसके सामाजिक प्रभाव और गुणवत्ता की भी जांच की जाती है। यह प्रशासन में पारदर्शिता लाता है क्योंकि जनता को व्यय और निर्णयों की जानकारी प्राप्त होती है। इससे अधिकारियों की जवाबदेही बढ़ती है और योजनाओं में होने वाली त्रुटियों को समुदाय की सहायता से सुधारा जा सकता है।

74. (A) राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार कर सकती है।
भारतीय बजटीय प्रक्रिया में लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अधिक वित्तीय शक्तियां प्राप्त हैं। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है और पारित होने के पश्चात इसे राज्यसभा को केवल सिफारिशों हेतु प्रेषित किया जाता है। राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती और न ही इसमें कोई ऐसा संशोधन कर सकती है जो लोकसभा हेतु बाध्यकारी हो। राज्यसभा के पास विधेयक को वापस करने हेतु केवल 14 दिन का समय होता है, जिसके पश्चात इसे दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है।

75. (A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
सूचना का अधिकार अधिनियम भ्रष्टाचार को रोकने हेतु एक अत्यंत प्रभावशाली साधन है क्योंकि यह प्रशासन की गोपनीयता को समाप्त करता है। जब नागरिकों को सरकारी फाइलों, निविदाओं और निर्णयों की प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त करने का विधिक अधिकार मिलता है, तो लोक सेवकों में उत्तरदायित्व का बोध बना रहता है। यह अधिकार जनता को शासन की निगरानी करने की शक्ति प्रदान करता है, जिससे पारदर्शिता में वृद्धि होती है। पारदर्शी व्यवस्था में अनियमितताओं की गुंजाइश न्यून हो जाती है, जो अंततः प्रशासन में शुचिता और जवाबदेही सुनिश्चित करती है।

76. (B) भर्ती कइयों को आकर्षित करती है जबकि चयन अनुपयुक्तों को बाहर कर देता है।
भर्ती को सकारात्मक प्रक्रिया इसलिए माना जाता है क्योंकि इसका उद्देश्य अधिकतम संख्या में लोगों को संगठन में आवेदन हेतु प्रोत्साहित करना है ताकि प्रतिभा का विशाल समूह उपलब्ध हो सके। इसके विपरीत, चयन एक नकारात्मक प्रक्रिया है क्योंकि इसमें विभिन्न परीक्षाओं और परीक्षणों के माध्यम से अयोग्य या कम योग्य उम्मीदवारों को क्रमिक रूप से बाहर निकाला जाता है। चयन का मुख्य कार्य उपलब्ध आवेदकों में से केवल सर्वश्रेष्ठ को चुनना और शेष को अस्वीकार करना है। इस प्रकार, भर्ती अवसर सृजित करती है और चयन सीमाएं निर्धारित करता है।

77. (C) विधिक-तार्किक सत्ता
मैक्स वेबर के अनुसार आधुनिक नौकरशाही का मुख्य आधार विधिक-तार्किक सत्ता है। यहाँ सत्ता किसी व्यक्ति के करिश्मे या परंपरा पर नहीं, बल्कि कानून द्वारा स्थापित निर्वैयक्तिक नियमों और पदों पर आधारित होती है। लोक सेवकों को अधिकार कानून से प्राप्त होते हैं और उनका पालन भी विधिक दायरे में रहकर ही किया जाता है। कर्मचारी और जनता नियमों के प्रति अपनी निष्ठा रखते हैं, न कि किसी विशिष्ट व्यक्ति के प्रति। यही कारण है कि यह प्रणाली स्थिर, पूर्वानुमानित और आधुनिक जटिल शासन हेतु सर्वाधिक कुशल मानी जाती है।

78. (D) प्रकोष्ठ (वेस्टिब्यूल) प्रशिक्षण
प्रकोष्ठ प्रशिक्षण में वास्तविक कार्यस्थल जैसा ही एक कृत्रिम वातावरण निर्मित किया जाता है। यहाँ प्रशिक्षुओं को उन्हीं उपकरणों और मशीनों पर प्रशिक्षण दिया जाता है जिनका उपयोग उन्हें वास्तविक कार्य में करना है। इसका मुख्य लाभ यह है कि प्रशिक्षु बिना वास्तविक उत्पादन को बाधित किए या महंगे उपकरणों को क्षति पहुँचाए सुरक्षित रूप से सीख सकते हैं। यह कार्य-बाह्य प्रशिक्षण का एक रूप है जो कार्य की जटिलता को देखते हुए व्यावहारिक कौशल विकसित करने हेतु आदर्श माना जाता है, जिससे कर्मचारी आत्मविश्वास के साथ कार्य कर सके।

79. (A) नीतिगत परिणामों के लिए सार्वजनिक रूप से प्रशंसा या दोष का पात्र नहीं होता है।
अनामिकता का सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि लोक सेवक पर्दे के पीछे रहकर कार्य करें। उनके द्वारा निर्मित नीतियों की सफलता या विफलता हेतु केवल संबंधित मंत्री ही संसद और जनता के प्रति जवाबदेह होता है। लोक सेवकों को उनके कार्यों हेतु सार्वजनिक रूप से न तो व्यक्तिगत गौरव मिलना चाहिए और न ही उनकी आलोचना होनी चाहिए। यह व्यवस्था लोक सेवकों को राजनीतिक विवादों से बचाती है और उन्हें निर्भीक होकर निष्पक्ष सलाह देने की अनुमति प्रदान करती है, जिससे प्रशासनिक व्यावसायिकता और स्थिरता अक्षुण्ण बनी रहती है।

80. (B) केवल 2 और 3
निर्णय लेने में नेतृत्व की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण और सक्रिय होती है। एक प्रभावी नेता केवल आदेश नहीं देता, बल्कि वह ऐसी परिस्थितियाँ निर्मित करता है जहाँ समूह के सदस्य मिलकर निर्णय ले सकें। समूह भागीदारी से न केवल निर्णयों की गुणवत्ता में सुधार होता है, बल्कि अनुयायी उन्हें अधिक तत्परता से स्वीकार भी करते हैं। नेतृत्व की शैली, चाहे वह लोकतांत्रिक हो या निरंकुश, निर्णयों के क्रियान्वयन और

NODIA

मानक निर्धारित करती है। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं की रक्षा करना और निजी क्षेत्र हेतु एक निष्पक्ष प्रतिस्पर्धी परिवेश निर्मित करना है। प्रशासन को अब अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और डिजिटल रूप से सक्षम होने की आवश्यकता है। यह परिवर्तन नौकरशाही को एक नियंत्रक के बजाय एक सक्षमकर्ता और कुशल प्रबंधक की भूमिका में ले आया है।

116. (D) व्यय की वैधता और नियमितता की जाँच के लिए पश्चात लेखापरीक्षा।
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की जाने वाली मुख्य लेखापरीक्षा 'कार्योत्तर' होती है। इसका अर्थ है कि यह अधिकारी धन व्यय होने के पश्चात सरकारी खातों की जांच करता है। वह यह देखता है कि क्या व्यय किया गया धन वास्तव में उसी उद्देश्य हेतु था जिसके लिए उसे अधिकृत किया गया था और क्या सभी विधिक प्रक्रियाओं का पालन किया गया। यह जाँच वित्तीय अनियमितताओं को उजागर करने और सरकार को संसद के प्रति जवाबदेह बनाने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिससे भविष्य में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित होता है।

117. (C) मजबूत और प्रभावी जवाबदेही तंत्र।
भ्रष्टाचार उन स्थितियों में पनपता है जहाँ पारदर्शिता न्यून होती है और प्रशासनिक प्रक्रियाएं अत्यंत जटिल तथा विलंबकारी होती हैं। जब लोक सेवकों के पास अत्यधिक विवेकाधीन शक्तियां होती हैं और उनकी आय उनके उत्तरदायित्वों की तुलना में कम होती है, तो वे अनैतिक लाभ की ओर आकर्षित हो सकते हैं। इसके विपरीत, एक सुदृढ़ और प्रभावी जवाबदेही तंत्र, जिसमें कड़ी निगरानी और दोषियों को त्वरित दंड का प्रावधान हो, भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक शक्तिशाली अवरोधक के रूप में कार्य करता है। ऐसे तंत्र की उपस्थिति से प्रशासन स्वच्छ और निष्पक्ष बना रहता है।

118. (A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।
ओम्बुड्समैन एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत संस्था है जिसका कार्य नागरिकों को कुप्रशासन और सरकारी अधिकारियों की मनमानी से सुरक्षा प्रदान करना है। भारत में इसी अवधारणा को क्रियान्वित करने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर लोकपाल की स्थापना की गई है। लोकपाल एक स्वतंत्र और उच्च स्तरीय निकाय है जो प्रधानमंत्री से लेकर निचले स्तर के लोक सेवकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर सकता है। ये संस्थाएं लोकतंत्र में जनता के प्रहरी के रूप में कार्य करती हैं और यह सुनिश्चित करती हैं कि प्रशासन अपनी शक्तियों का प्रयोग न्यायसंगत तरीके से करे।

119. (D) प्रारंभ में कदाचार के विशिष्ट आरोपों का विवरण देता है।
आरोप-पत्र अनुशासनात्मक कार्यवाही का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रलेख है। यह उस समय जारी किया जाता है जब प्रथम दृष्टया किसी कर्मचारी के विरुद्ध कदाचार या अनुशासनहीनता के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसमें उन विशिष्ट आरोपों और नियमों के उल्लंघन का विवरण होता है जिनके लिए कर्मचारी को जिम्मेदार माना गया है। इसके माध्यम से कर्मचारी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने और स्पष्टीकरण देने का अवसर प्रदान किया जाता है। यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन सुनिश्चित करता है, ताकि किसी भी कर्मचारी को बिना अपना पक्ष रखे दंडित न किया जा सके।

120. (A) एक नियोक्ता और कर्मचारियों के एक समूह के बीच बातचीत।
सामूहिक सौदेबाजी औद्योगिक संबंधों की एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ कर्मचारी और प्रबंधन मिलकर कार्य की शर्तों, वेतन, कार्य के घंटों और अन्य लाभों पर वार्ता करते हैं। इसका उद्देश्य संघर्षों को आपसी सहमति से सुलझाना और एक लिखित समझौते तक पहुँचना है। यह प्रक्रिया व्यक्तिगत कर्मचारी की तुलना में समूह की शक्ति को बढ़ाती है और कार्यस्थल पर लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देती है। यह विवादों के समाधान का एक शांतिपूर्ण और प्रभावी तरीका है, जो दोनों पक्षों के हितों में उचित संतुलन स्थापित करने का निरंतर प्रयास करता है।

121. (C) कर्मकांडवाद (रिचुअलिज्म)
नौकरशाही में कर्मकांडवाद वह स्थिति है जहाँ नियम स्वयं में साध्य बन जाते हैं और उनके मूल उद्देश्य की अनदेखी कर दी जाती है। रॉबर्ट मर्टन के अनुसार, कर्मचारी नियमों के इतने अभ्यस्त हो जाते हैं कि वे बदलती परिस्थितियों के प्रति अपनी संवेदनशीलता खो देते हैं। यहाँ कार्य की सफलता को इस आधार पर मापा जाता है कि नियमों का पालन कितनी कड़ाई से किया गया, भले ही उससे वास्तविक समस्या का समाधान न हो। यह प्रवृत्ति प्रशासन में जड़ता, विलंब और लचीलेपन की कमी उत्पन्न करती है, जिससे अंततः संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति में बाधा पहुँचती है।

122. (A) अनुयायियों को लक्ष्यों के लिए स्वार्थ से ऊपर उठने के लिए प्रेरित करना।
नेतृत्व की परिवर्तनकारी शैली अनुयायियों में आत्मविश्वास जागृत करने और उन्हें संगठन के व्यापक विजन के प्रति समर्पित करने पर केंद्रित है। एक परिवर्तनकारी नेता अपनी प्रेरणा और बौद्धिक उद्दीपन के माध्यम से कर्मचारियों की मानसिकता में सकारात्मक बदलाव लाता है। वह उन्हें केवल पुरस्कार हेतु कार्य करने के बजाय, व्यक्तिगत विकास और समूह कल्याण हेतु कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। यह शैली नवीनता, सृजनात्मकता और संगठनात्मक संस्कृति में सुधार लाने हेतु जानी जाती है, जिससे कर्मचारी अपनी क्षमताओं का सर्वोत्तम प्रदर्शन कर पाते हैं।

123. (D) उदारीकरण की नीति।
1991 के आर्थिक संकट के पश्चात भारत ने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति अंगीकार की। इसके परिणामस्वरूप प्रशासन का केंद्र 'विकास योजना' से हटकर 'बाजार आधारित विकास' की ओर चला गया। अब राज्य की भूमिका सीधे उत्पादन करने के बजाय निजी निवेश को सुगम बनाने और नियामक ढांचे को सुदृढ़ करने की हो गई। इस बदलाव ने लाइसेंस राज को समाप्त किया और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया। यह आधुनिक प्रशासनिक सुधारों का एक महत्वपूर्ण अंग है जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक स्तर पर खोला और सरकारी नियंत्रण को सीमित किया।

Downloaded from www.pdf.tube

मूल्यांकन रिपोर्ट का उपयोग किया जाता है, जिसमें कर्मचारी के पूरे वर्ष के कार्य का विधिवत रिकॉर्ड रखा जाता है। शिकायत निवारण हेतु संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र जैसा मंच निर्मित किया गया है जहाँ कर्मचारी और प्रबंधन आपसी बातचीत से समस्याओं को सुलझाते हैं। ये सभी तत्व कुशल कार्मिक प्रबंधन के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं।

191. (A) निष्पक्ष जांच के लिए कर्तव्यों से अस्थायी रूप से हटाया जाना।
निलंबन एक प्रशासनिक कार्रवाई है, न कि कोई अंतिम दंड। इसका उपयोग तब किया जाता है जब किसी कर्मचारी के विरुद्ध गंभीर कदाचार के आरोपों की जांच गतिमान हो। निलंबन का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संबंधित कर्मचारी जांच की प्रक्रिया को प्रभावित न कर सके, साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ न कर सके या गवाहों को डरा न सके। निलंबन के दौरान कर्मचारी को पद के कर्तव्यों से मुक्त रखा जाता है किंतु उसे जीवन निर्वाह हेतु एक निश्चित भत्ता प्रदान किया जाता है। जांच पूर्ण होने पर प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर उसे या तो सेवा में बहाल किया जाता है या उचित दंड प्रदान किया जाता है।

192. (B) उर्ध्वमुखी और क्षैतिज संचार।
नौकरशाही की पदानुक्रमित संरचना को प्रायः एक पिरामिड के रूप में देखा जाता है जहाँ आदेश ऊपर से नीचे की ओर सुगमता से प्रवाहित होते हैं। यद्यपि, यही संरचना उर्ध्वमुखी संचार (नीचे से ऊपर सुझाव या प्रतिपुष्टि) में बाधा उत्पन्न करती है क्योंकि सूचना को अनेक स्तरों से गुजरना पड़ता है, जिससे वह विकृत हो सकती है। इसी प्रकार, विभिन्न विभागों के बीच क्षैतिज संचार भी बाधित होता है क्योंकि कर्मचारी अपने विभाग की सीमाओं में आबद्ध रहते हैं। यह संचार अंतराल संगठन की लचीलापन न्यून करता है और महत्वपूर्ण सूचनाओं को निर्णयकर्ताओं तक समय पर पहुँचने से रोकता है, जिससे कार्यकुशलता प्रभावित होती है।

193. (B) सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन।
विकास प्रशासन में 'विकास' शब्द का अर्थ केवल आर्थिक विकास दर में वृद्धि नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण समाज के गुणात्मक और संरचनात्मक परिवर्तन को परिलक्षित करता है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन और सामाजिक न्याय जैसे महत्वपूर्ण आयाम सम्मिलित हैं। इसका उद्देश्य समाज को पारंपरिक और पिछड़ेपन की स्थिति से निकालकर एक आधुनिक और समतावादी समाज की ओर अग्रसर करना है। राजनीतिक रूप से, इसका अर्थ लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रसार और निर्णय प्रक्रिया में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना है। इस प्रकार, विकास प्रशासन एक बहुआयामी प्रक्रिया है जो समाज के समग्र कल्याण हेतु समर्पित है।

194. (A) संचित निधि से धन निकालने के लिए अधिकृत करता है।
संविधान के अनुसार, सरकार संसद की स्पष्ट स्वीकृति के बिना भारत की संचित निधि से कोई भी धनराशि व्यय नहीं कर सकती है। बजट पर विस्तृत चर्चा और अनुदान की मांगों पर मतदान के पश्चात, सरकार संसद में 'विनियोग विधेयक' प्रस्तुत करती है। इस विधेयक के पारित होकर 'विनियोग अधिनियम' बनने पर ही सरकार को विधिक रूप से संचित निधि से धन आहरण और उसे विभिन्न विभागों पर व्यय करने का अधिकार प्राप्त होता है। यह वित्तीय नियंत्रण की एक अनिवार्य प्रक्रिया है जो यह सुनिश्चित करती है कि कार्यपालिका विधायी स्वीकृति के बिना सार्वजनिक धन का उपयोग किसी भी स्थिति में न कर सके।

195. (A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
सुशासन हेतु जवाबदेही एक अनिवार्य शर्त है क्योंकि अनियंत्रित शक्ति का स्वभाव अक्सर भ्रष्ट होने की ओर प्रवृत्त होता है। जब सार्वजनिक अधिकारियों को यह बोध होता है कि उनके प्रत्येक कार्य और निर्णय की समीक्षा की जा सकती है और उन्हें त्रुटियों हेतु जिम्मेदार ठहराया जाएगा, तो वे अधिक सावधानी और ईमानदारी से कार्य करते हैं। जवाबदेही तंत्र के अभाव में प्रशासन निरंकुश हो सकता है, जिससे जनहित की उपेक्षा और संसाधनों की बर्बादी होती है। इसलिए, लोकतंत्र में जवाबदेही केवल एक नियम नहीं, बल्कि प्रशासनिक शुचिता और नागरिक अधिकारों की रक्षा का सर्वाधिक प्रभावी सुरक्षा कवच माना जाता है।

196. (D) संथानम समिति
भारत में भ्रष्टाचार विरोधी ढांचे को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 1962 में के. संथानम की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने गहन अध्ययन के पश्चात यह निष्कर्ष निकाला कि भ्रष्टाचार को रोकने हेतु एक स्वतंत्र केंद्रीय संस्था की नितांत आवश्यकता है। समिति की सिफारिशों पर अमल करते हुए भारत सरकार ने 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की। प्रारंभ में यह एक कार्यकारी निकाय था, किंतु पश्चात में इसे वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। केंद्रीय सतर्कता आयोग आज केंद्र सरकार के भीतर भ्रष्टाचार पर नियंत्रण रखने और सतर्कता मामलों पर परामर्श देने वाली सर्वोच्च संस्था है।

NODIA

197. (C) गलत कार्य या भ्रष्टाचार को उजागर करना।
व्हिसलब्लोइंग वह कार्य है जिसमें संगठन का कोई कर्मचारी अपने ही विभाग या संस्था के भीतर हो रहे भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी, अनैतिक कार्यों या जन सुरक्षा के संकटों की सूचना सक्षम अधिकारियों या जनता को प्रदान करता है। सूचना प्रदाता अक्सर जोखिम उठाकर सत्य सामने लाता है ताकि व्यवस्था में सुधार हो सके। भारत में ऐसे व्यक्तियों की सुरक्षा हेतु 'व्हिसलब्लोअर प्रोटेक्शन अधिनियम' निर्मित किया गया है। यह पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने का एक साहसी तरीका है, जो संगठन के भीतर से ही भ्रष्टाचार की जड़ों पर प्रहार करता है और सार्वजनिक हित की रक्षा करने में अत्यंत सहायक सिद्ध होता है।

198. (B) लोक सेवाओं के लिए भर्ती करना और कार्मिक मामलों पर सलाह देना।
लोक सेवा आयोग, जैसे भारत में संघ लोक सेवा आयोग, एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है जिसका मुख्य उत्तरदायित्व लोक सेवाओं हेतु निष्पक्ष और योग्यता-आधारित भर्ती प्रक्रिया संचालित करना है। यह सुनिश्चित करता है कि सिविल सेवा में नियुक्तियां बिना किसी राजनीतिक पक्षपात के केवल

STUDYING FROM PDFs?

THINK AGAIN.

If you are studying only from PDFs,
you are wasting valuable time.

Research shows that learning from

PRINTED BOOKS has up to

4× HIGHER RETENTION

than studying from screens.

PRINT BOOK = BETTER MEMORY

PDF = LOWER RETENTION

Those who study from **PRINTED BOOKS**
move **AHEAD.**

Others are left **BEHIND**
in competition.

In competitive exams,
being average is not enough.

STAY ONE STEP AHEAD.

कार्यक्षमता प्रभावित होती है। प्रभावी प्रबंधन का लक्ष्य इन बाधाओं को पहचानना और उन्हें दूर करने के उपाय करना है।

133. (C) उत्तरदेयता (आंसरिबिलिटी)
जवाबदेही और उत्तरदेयता एक-दूसरे के पूरक हैं। जवाबदेही का अर्थ केवल कार्य करना नहीं है, बल्कि अपने कार्यों और निर्णयों के पीछे के तर्कों और परिणामों की व्याख्या करना भी है। एक जवाबदेह अधिकारी वह है जो अपने पद के दुरुपयोग या किसी भी त्रुटि हेतु जनता या उच्च अधिकारियों के समक्ष उत्तर देने हेतु विधिक रूप से बाध्य है। यह अवधारणा सत्ता की मनमानी को नियंत्रित करती है और लोक प्रशासन में शुचिता लाती है। बिना उत्तरदेयता के जवाबदेही केवल एक औपचारिक शब्द बनकर रह जाती है, जो शासन के वास्तविक लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रहती है।

134. (B) विवादों को सुलझाने के लिए प्रतिनिधियों की एक संयुक्त परिषद।
ह्विटली परिषदें ब्रिटेन में विकसित एक विशिष्ट तंत्र हैं, जिन्हें भारत में संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र के रूप में अंगीकार किया गया है। ये परिषदें सरकार और उसके कर्मचारियों के बीच संवाद और सहयोग को प्रोत्साहित करने हेतु निर्मित की गई हैं। इनमें नियोक्ता और कर्मचारियों के प्रतिनिधि एक साथ बैठते हैं और वेतन, सेवा शर्तों तथा कल्याण से संबंधित विषयों पर चर्चा करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य औद्योगिक अशांति को रोकना और एक ऐसी कार्य संस्कृति विकसित करना है जहाँ विवादों को हड़ताल के स्थान पर वार्ता और समझ के माध्यम से शांतिपूर्वक सुलझाया जा सके।

135. (A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
मैक्स वेबर का नौकरशाही का 'आदर्श प्रारूप' एक काल्पनिक और सैद्धांतिक प्रारूप है, जो संगठन की उन विशेषताओं को दर्शाता है जो उसे पूर्णतः तार्किक और कुशल बनाती हैं। यह किसी वास्तविक संगठन का अक्षरशः वर्णन नहीं है, बल्कि विश्लेषण हेतु एक मानदंड है। इसके माध्यम से समाजशास्त्री यह देख सकते हैं कि कोई वास्तविक संगठन विधिक-तार्किक सत्ता के शुद्ध स्वरूप के कितना समीप या दूर है। वेबर का विश्वास था कि जटिल आधुनिक समाज की आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु नियमों पर आधारित यह व्यवस्था ही सर्वाधिक प्रभावी ढांचा है।

136. (A) प्रशिक्षण विशिष्ट और कार्य-उन्मुख है; शिक्षा व्यापक है।
प्रशिक्षण और शिक्षा दोनों ही ज्ञानार्जन के साधन हैं, किंतु उनके उद्देश्य और क्षेत्र भिन्न हैं। प्रशिक्षण का मुख्य ध्यान किसी विशेष कार्य को करने हेतु आवश्यक विशिष्ट कौशल और दक्षता विकसित करने पर होता है। यह तात्कालिक और व्यावहारिक होता है। इसके विपरीत, शिक्षा एक व्यापक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य व्यक्ति के संपूर्ण मानसिक, बौद्धिक और चारित्रिक विकास को उन्नत करना है। शिक्षा दृष्टिकोण विकसित करती है और सोचने की क्षमता प्रदान करती है, जबकि प्रशिक्षण उस शिक्षा को विशिष्ट व्यावसायिक संदर्भ में लागू करने का व्यावहारिक तरीका सिखाता है।

137. (C) कर्मचारी की सेवा समाप्त कर दी जाती है लेकिन उसे बाद में पुनः नियोजित किया जा सकता है।
सरकारी सेवा में 'हटाना' एक गंभीर दंड है जिसमें कर्मचारी की वर्तमान सेवा को समाप्त कर दिया जाता है। यद्यपि, यह 'बर्खास्तगी' से इस अर्थ में भिन्न है कि हटाए गए कर्मचारी को भविष्य में किसी अन्य सरकारी सेवा के लिए विधिक रूप से अयोग्य नहीं माना जाता। बर्खास्तगी में भविष्य के समस्त सरकारी नियोजन के द्वार बंद हो जाते हैं। अतः हटाना एक कठोर दंड होने के उपरांत भी कर्मचारी को भविष्य में सुधार और द्वितीय अवसर की संभावना प्रदान करता है, बशर्ते वह नवीन पदों की विधिक पात्रता को पूर्ण करता हो।

138. (A) जब पदोन्नति पक्षपात और भाई-भतीजावाद पर आधारित हो।
संगठन में कर्मचारियों का मनोबल उस समय सर्वाधिक गिरता है जब उन्हें अनुभव होता है कि उनकी मेहनत और योग्यता के स्थान पर चापलूसी या व्यक्तिगत संबंधों को महत्व प्रदान किया जा रहा है। पक्षपातपूर्ण पदोन्नति से ईमानदार और सक्षम कर्मचारियों में निराशा और असुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है। इससे कार्य के प्रति उनकी निष्ठा न्यून हो जाती है और उनमें संगठन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ती है। मनोबल अक्षुण्ण रखने हेतु यह अनिवार्य है कि पदोन्नति और पुरस्कार की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ और केवल प्रदर्शन पर आधारित हो।

139. (D) बाजार तंत्र, दक्षता और निष्पादन माप।
नवीन सार्वजनिक प्रबंधन सार्वजनिक प्रशासन का एक ऐसा दृष्टिकोण है जो सरकारी क्षेत्र में निजी क्षेत्र की प्रबंधन तकनीकों को अपनाने का समर्थन करता है। यह पदानुक्रम और कठोर नियमों के स्थान पर परिणामों, दक्षता और लागत प्रभावी समाधानों पर बल देता है। इसमें नागरिकों को ग्राहकों के रूप में देखा जाता है और सेवाओं के वितरण में बाजार की प्रतिस्पर्धा को सम्मिलित किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य नौकरशाही की कठोरता को न्यून करना और प्रशासन को अधिक गतिशील तथा उत्तरदायी बनाना है, जहाँ प्रदर्शन का मूल्यांकन स्पष्ट मानकों के आधार पर हो सके।

140. (C) केवल 1 और 2
वित्तीय प्रशासन में बजट सरकार की अनुमानित आय और प्रस्तावित व्यय का एक औपचारिक विवरण होता है, जो भविष्य की कार्ययोजना को दर्शाता है। लेखापरीक्षा एक महत्वपूर्ण नियंत्रण तंत्र है जो यह जाँचना सुनिश्चित करता है कि व्यय वास्तव में नियमों के अनुसार और स्वीकृत सीमा के भीतर किया गया है। बजट के अधिनियमन में विधायिका की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण और अनिवार्य है, क्योंकि बिना संसद की अनुमति के सरकार कोई भी धनराशि व्यय नहीं कर सकती और न ही कोई नवीन कर अधिरोपित कर सकती है। अतः विधायी स्वीकृति बजट प्रक्रिया का केंद्रीय स्तंभ है।

141. (C) नौकरशाही के दुष्परिणाम या इसकी कमियां।
'नौकरशाही विकृति' उन नकारात्मक व्यवहारों और समस्याओं को संदर्भित करती है जो नौकरशाही की अत्यधिक नियम-बद्धता और पदानुक्रम के कारण उत्पन्न होती हैं। इसमें

Click Here to Buy book on Amazon

बिना किसी भय के निष्पक्ष सलाह प्रदान करे और एक बार नीति निर्धारित हो जाने के पश्चात, उसे पूरी निष्ठा से क्रियान्वित करे। इन दोनों के बीच आपसी अविश्वास शासन को पंगु बना देता है, इसलिए निरंतर संवाद महत्वपूर्ण है।

159. (A) अहस्तक्षेपकारी (लेसफेयर)
अहस्तक्षेपकारी नेतृत्व शैली में नेता अपनी शक्ति का न्यूनतम उपयोग करता है और अधीनस्थों को कार्य करने तथा निर्णय लेने की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करता है। इसमें नेता की भूमिका केवल संसाधन उपलब्ध कराने और बाहरी संपर्क बनाए रखने तक सीमित होती है। वह समूह की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेता और न ही कोई प्रत्यक्ष मार्गदर्शन प्रदान करता है। यह शैली केवल तभी सफल होती है जब कर्मचारी अत्यधिक अनुभवी, आत्म-प्रेरित और अपने कार्य में विशेषज्ञ हों। यद्यपि, कम अनुभवी टीम के प्रकरण में यह शैली अनुशासनहीनता और लक्ष्यों के प्रति भ्रम उत्पन्न कर सकती है।

160. (C) P-4, Q-1, R-2, S-3
जवाबदेही यह सुनिश्चित करती है कि सार्वजनिक अधिकारी अपने कार्यों और निर्णयों हेतु विधिक और नैतिक रूप से उत्तरदायी हों। पारदर्शिता का अर्थ है कि प्रशासनिक प्रक्रियाएं और सूचनाएं जनता हेतु खुली और सुलभ होनी चाहिए ताकि भ्रष्टाचार की गुंजाइश न रहे। विधि का शासन एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ सभी कार्य एक निष्पक्ष और समान रूप से लागू होने वाले विधिक ढांचे के अंतर्गत किए जाते हैं। भागीदारी यह सुनिश्चित करती है कि नागरिकों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनी बात रखने का समुचित अवसर प्राप्त हो, जिससे लोकतंत्र और सुशासन की नींव निरंतर सुदृढ़ होती है।

161. (B) शब्दों और प्रतीकों के अर्थ से जुड़ी समस्याएं।
संचार में शब्दार्थ संबंधी बाधाएं तब उत्पन्न होती हैं जब प्रेषक और प्राप्तकर्ता शब्दों, प्रतीकों या संकेतों का भिन्न-भिन्न अर्थ निकालते हैं। यह अक्सर अस्पष्ट भाषा, जटिल तकनीकी शब्दावली या त्रुटिपूर्ण अनुवाद के कारण होता है। उदाहरण हेतु, एक ही शब्द का भिन्न संदर्भों में अलग अर्थ हो सकता है, जिससे संदेश का मूल भाव लुप्त हो जाता है। यदि प्राप्तकर्ता संदेश को उस अर्थ में नहीं समझ पाता जिसमें प्रेषक ने उसे प्रेषित किया है, तो प्रभावी संचार विफल हो जाता है। इसलिए, सरल और स्पष्ट भाषा का प्रयोग इन बाधाओं को दूर करने हेतु अनिवार्य है।

162. (A) आर्थिक गतिविधि के सुगमकर्ता के रूप में एक नई भूमिका के अनुकूल होना।
उदारीकरण के पश्चात भारतीय नौकरशाही के सम्मुख सबसे बड़ी चुनौती अपनी पारंपरिक 'नियंत्रक' की छवि को परिवर्तित कर एक 'सुगमकर्ता' की भूमिका निभाना है। अब प्रशासन का कार्य केवल प्रतिबंध अधिरोपित करना नहीं है, बल्कि निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित करना और आर्थिक विकास हेतु अनुकूल वातावरण तैयार करना है। इसके लिए नौकरशाहों को अधिक लचीला, व्यावसायिक और बाजार-उन्मुख होने की आवश्यकता है। यह बदलाव पुरानी मानसिकता को त्यागने और नवीन तकनीक तथा वैश्विक मानकों को अपनाने की मांग करता है, जो प्रशासनिक सुधारों की दिशा में एक सतत प्रक्रिया है।

163. (C) कार्यपालिका द्वारा अनुमानों की तैयारी और निरूपण।
बजटीय प्रक्रिया का प्रथम और अत्यंत महत्वपूर्ण चरण कार्यपालिका द्वारा विभिन्न विभागों की वित्तीय आवश्यकताओं का आकलन करना और बजट अनुमान तैयार करना है। भारत में, यह कार्य वित्त मंत्रालय द्वारा अन्य मंत्रालयों के सहयोग से संपन्न किया जाता है। इसमें आगामी वर्ष हेतु संभावित आय और व्यय का सूक्ष्मता से विश्लेषण किया जाता है। एक बार जब बजट का प्रारूप तैयार हो जाता है, तभी उसे विधायी स्वीकृति हेतु संसद में प्रस्तुत किया जाता है। यह चरण सरकार की नीतिगत प्राथमिकताओं और आर्थिक दृष्टिकोण को वित्तीय ढांचे में ढालने का ठोस आधार प्रदान करता है।

164. (D) भ्रष्टाचार के अवसरों को कम करने के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाना।
निवारक सतर्कता भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक दीर्घकालिक और सकारात्मक रणनीति है जो समस्या उत्पन्न होने से पूर्व ही उसे रोकने पर ध्यान केंद्रित करती है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक प्रणालियों में विद्यमान उन त्रुटियों और जटिलताओं को दूर करना है जिनका लाभ उठाकर भ्रष्टाचार किया जाता है। इसमें प्रक्रियाओं का सरलीकरण, पारदर्शिता में वृद्धि, विवेकाधीन शक्तियों को न्यून करना और सूचना तकनीक का व्यापक उपयोग सम्मिलित है। जब व्यवस्था पारदर्शी और सुगम होती है, तो भ्रष्टाचार दुष्कर हो जाता है। यह दंडात्मक सतर्कता से अधिक प्रभावी है क्योंकि यह भ्रष्टाचार के मूल कारणों पर प्रहार करती है।

165. (A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
लोकपाल की संस्था की प्रभावशीलता उसकी स्वायत्तता और स्वतंत्रता पर टिकी है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष में यह अनिवार्य है कि जांच करने वाला निकाय राजनीतिक या कार्यकारी दबाव से पूर्णतः मुक्त हो। यदि लोकपाल स्वतंत्र नहीं होगा, तो वह प्रधानमंत्री, मंत्रियों या वरिष्ठ लोक सेवकों जैसे उच्च पदस्थ व्यक्तियों के विरुद्ध निष्पक्ष जांच करने में अक्षम होगा। इसकी स्वतंत्रता ही इसे बिना किसी भय या पक्षपात के कार्य करने की विधिक शक्ति प्रदान करती है, जिससे जनता का इस संस्था पर विश्वास अक्षुण्ण बना रहता है और सार्वजनिक जीवन में उच्च नैतिक मानकों की स्थापना संभव होती है।

166. (B) वरिष्ठता का सिद्धांत
वरिष्ठता का सिद्धांत पदोन्नति की एक ऐसी विधि है जहाँ केवल कर्मचारी की सेवा की अवधि को ही वरीयता प्रदान की जाती है। इस प्रणाली में यह माना जाता है कि दीर्घकालिक अनुभव अपने आप में योग्यता का प्रमाण है। यहाँ एक ही श्रेणी में सर्वाधिक समय तक कार्य करने वाले कर्मचारी को पदोन्नत किया जाता है, भले ही कोई कनिष्ठ कर्मचारी अधिक प्रतिभाशाली या कुशल क्यों न हो। यह पद्धति अत्यंत वस्तुनिष्ठ है और इसमें प्रबंधन के पक्षपात की कोई संभावना नहीं होती, किंतु इसकी मुख्य आलोचना यह है कि यह असाधारण प्रदर्शन

NODIA

150. (B) सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक विकास को बढ़ावा देना।
भारत जैसे विकासशील राष्ट्र में विकास योजना का उद्देश्य केवल सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि करना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी है कि विकास का लाभ समाज के अत्यंत पिछड़े और वंचित वर्गों तक पहुँचे। इसके लिए राज्य को अर्थव्यवस्था में सक्रिय हस्तक्षेप करना पड़ता है ताकि गरीबी, असमानता और बेरोजगारी जैसी समस्याओं का समाधान किया जा सके। विकास योजना का मुख्य दर्शन यह है कि आर्थिक प्रगति मानवीय गरिमा और सामाजिक समानता की कीमत पर नहीं होनी चाहिए, बल्कि वह इन मूल्यों को सुदृढ़ करने का एक सशक्त माध्यम बननी चाहिए।

151. (D) व्यय की बुद्धिमत्ता और मितव्ययिता की जांच करना।
औचित्य लेखापरीक्षा पारंपरिक लेखापरीक्षा से एक चरण आगे की प्रक्रिया है। यह केवल यह नहीं देखती कि व्यय नियमों के अनुसार हुआ है या नहीं, बल्कि यह व्यय की बुद्धिमत्ता और आवश्यकता पर भी प्रश्न उठाती है। इसमें परीक्षक यह जाँचना सुनिश्चित करता है कि क्या लोक सेवक ने सार्वजनिक धन को उसी सावधानी से व्यय किया है जैसे एक सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति अपना स्वयं का धन व्यय करता है। इसका उद्देश्य धन की बर्बादी को रोकना और यह सुनिश्चित करना है कि सार्वजनिक संसाधनों का उपयोग अधिकतम जनकल्याण और मितव्ययिता के साथ किया गया है।

152. (A) निजी लाभ के बदले सार्वजनिक सेवा का विशिष्ट आदान-प्रदान।
'क्विड प्रो क्वो' एक लैटिन वाक्यांश है जिसका अर्थ है 'कुछ के बदले कुछ'। भ्रष्टाचार के संदर्भ में यह उस स्थिति को दर्शाता है जहाँ एक लोक सेवक किसी व्यक्ति को अनुचित लाभ पहुँचाने या उसका कार्य करने के बदले में रिश्वत, उपहार या किसी व्यक्तिगत उपकार की मांग करता है। यह एक द्विपक्षीय लेनदेन है जहाँ दोनों पक्ष आपसी लाभ हेतु कानून का उल्लंघन करते हैं। इस प्रकार का भ्रष्टाचार प्रशासन की निष्पक्षता को पूर्णतः समाप्त कर देता है और केवल उन लोगों को लाभ पहुँचाता है जो भुगतान करने में सक्षम हैं, जिससे सामाजिक न्याय प्रभावित होता है।

153. (C) 30 दिन
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुसार, जब कोई नागरिक किसी सार्वजनिक प्राधिकरण से जानकारी मांगता है, तो जन सूचना अधिकारी का यह विधिक दायित्व है कि वह अनुरोध प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर सूचना उपलब्ध कराए। यदि मांगी गई सूचना किसी अन्य विभाग से संबंधित है, तो यह समय सीमा किंचित बढ़ सकती है, किंतु सामान्यतः इसे 30 दिन ही रखा गया है। इस समय सीमा का उल्लंघन करने पर अधिकारी पर आर्थिक दंड अधिरोपित किया जा सकता है। यह प्रावधान प्रशासनिक तत्परता सुनिश्चित करने और नागरिकों को समयबद्ध सेवा प्रदान करने हेतु किया गया है।

154. (A) लोकायुक्त की शक्तियां सभी राज्यों में समान हैं।
भारत में लोकायुक्त संस्था की स्थापना विभिन्न राज्यों द्वारा अपने स्वयं के अधिनियमों के माध्यम से की गई है, जिसके कारण उनकी शक्तियों, संरचना और अधिकार क्षेत्र में महत्वपूर्ण भिन्नताएं पाई जाती हैं। उदाहरण हेतु, कुछ राज्यों में लोकायुक्त के पास मंत्रियों की जांच करने की शक्ति है, जबकि अन्य में नहीं। कुछ राज्यों में मुख्यमंत्री इसके दायरे में आते हैं, तो कुछ में उन्हें बाहर रखा गया है। यद्यपि सभी का मूल उद्देश्य भ्रष्टाचार को रोकना है, किंतु उनकी कार्यप्रणाली में एकरूपता का अभाव उनकी प्रभावशीलता को राज्य-दर-राज्य भिन्न-भिन्न बना देता है।

155. (D) 19वीं शताब्दी का संयुक्त राज्य अमेरिका।
'लूट पद्धति' का जन्म और विकास 19वीं शताब्दी के अमेरिका में हुआ, विशेषकर राष्ट्रपति एंड्रयू जैक्सन के कार्यकाल के दौरान। इस प्रणाली में यह माना जाता था कि 'विजेता को लूट का माल प्राप्त होता है', जिसका अर्थ था कि चुनाव जीतने वाला दल सरकारी पदों पर अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं को नियुक्त कर सकता था। इससे प्रशासन में भारी भ्रष्टाचार, अक्षमता और अस्थिरता आई क्योंकि प्रत्येक चुनाव के पश्चात संपूर्ण कर्मचारी परिवर्तित कर दिए जाते थे। इसके दुष्परिणामों को देखते हुए पश्चात में योग्यता प्रणाली को वहां विधिपूर्वक अपनाया गया।

156. (B) प्रशिक्षण
प्रशिक्षण कार्मिक प्रशासन का एक अनिवार्य अंग है जिसका मुख्य लक्ष्य लोक सेवकों को उनके विशिष्ट कार्यों के निष्पादन हेतु आवश्यक ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण प्रदान करना है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति की वर्तमान क्षमताओं और कार्य की बदलती मांगों के बीच के अंतर को न्यून करती है। प्रशिक्षण न केवल तकनीकी दक्षता बढ़ाता है, बल्कि यह कर्मचारी को नवीन चुनौतियों और जटिल परिस्थितियों के समाधान हेतु मानसिक रूप से भी तैयार करता है। एक भली-भांति प्रशिक्षित कार्यबल किसी भी संगठन की उत्पादकता और सेवा की गुणवत्ता को उच्चतम स्तर पर ले जाने में सक्षम होता है।

157. (C) अनौपचारिक सामाजिक गतिशीलता और मानवीय तत्व।
मैक्स वेबर का नौकरशाही मॉडल अत्यधिक यांत्रिक और औपचारिक संरचना पर केंद्रित था। इसकी सबसे बड़ी न्यूनता यह थी कि इसने संगठन के भीतर मानवीय भावनाओं, अनौपचारिक समूहों और आपसी सामाजिक संबंधों के प्रभाव की उपेक्षा की। पश्चात के विचारकों ने यह सिद्ध किया कि कर्मचारी केवल नियमों से नहीं, बल्कि अपनी सामाजिक आवश्यकताओं और कार्यस्थल के अनौपचारिक परिवेश से भी प्रेरित होते हैं। वेबर ने नौकरशाही को एक ऐसी निर्वैयक्तिक मशीन के रूप में देखा जो दक्षता तो लाती है, किंतु वह मानवीय व्यवहार की जटिलताओं और संगठन की सामाजिक गतिशीलता को समझने में विफल रही।

158. (D) आपसी सम्मान, सहयोग और समझ का।
संसदीय लोकतंत्र की सफलता हेतु मंत्री और लोक सेवक के बीच एक परिपक्व और सहयोगात्मक संबंध नितांत अनिवार्य है। मंत्री को लोक सेवक की प्रशासनिक विशेषज्ञता और अनुभव का सम्मान करना चाहिए, जबकि लोक सेवक को मंत्री के राजनीतिक जनादेश और लोकतांत्रिक सर्वोच्चता को पूर्णतः स्वीकार करना चाहिए। आदर्श स्थिति वह है जहाँ लोक सेवक

NODIA

124. (B) सार्वजनिक नीति और आर्थिक प्रबंधन।
बजट केवल आय और व्यय का लेखा-जोखा नहीं है, बल्कि यह सरकार की प्राथमिकताओं और भविष्य की योजनाओं का एक महत्वपूर्ण प्रलेख है। इसके माध्यम से सरकार अपनी सार्वजनिक नीतियों को वित्तीय रूप प्रदान करती है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य या रक्षा पर होने वाला व्यय। यह देश के आर्थिक प्रबंधन का एक सशक्त साधन है, जिसका उपयोग मुद्रास्फीति नियंत्रण, संसाधनों के पुनर्वितरण और आर्थिक वृद्धि को गति प्रदान करने हेतु किया जाता है। संक्षेप में, बजट एक ऐसा वित्तीय दर्पण है जिसमें सरकार के सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण की स्पष्ट झलक मिलती है।

125. (C) उसी सार्वजनिक प्राधिकरण में एक वरिष्ठ अधिकारी।
सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत यदि जन सूचना अधिकारी सूचना प्रदान करने से मना कर देता है या निर्धारित समय में उत्तर नहीं देता, तो आवेदक प्रथम अपील दायर कर सकता है। यह अपील उसी विभाग या सार्वजनिक प्राधिकरण में जन सूचना अधिकारी से वरिष्ठ रैंक के नामित अधिकारी के समक्ष की जाती है। प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का कर्तव्य है कि वह मामले की निष्पक्ष जांच करे और अपना निर्णय प्रदान करे। यदि आवेदक प्रथम अपील के निर्णय से भी संतुष्ट नहीं है, तो वह द्वितीय अपील हेतु सूचना आयोग के पास जा सकता है।

126. (D) राज्य के राज्यपाल।
लोकायुक्त की नियुक्ति राज्य स्तर पर राज्यपाल द्वारा की जाती है। नियुक्ति की प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाए रखने हेतु राज्यपाल सामान्यतः राज्य के मुख्यमंत्री, विधानसभा में विपक्ष के नेता और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर कार्य करते हैं। लोकायुक्त का पद एक स्वतंत्र और गरिमापूर्ण पद है, जिसका उद्देश्य उच्च राजनीतिक और प्रशासनिक पदों पर आसीन व्यक्तियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की जांच करना है। राज्यपाल द्वारा की गई यह नियुक्ति सुनिश्चित करती है कि संस्था राज्य सरकार के प्रत्यक्ष दबाव से मुक्त रहकर कार्य कर सके।

127. (A) पदोन्नति अनुशासनात्मक कार्रवाई का एक रूप है।
पदोन्नति एक सकारात्मक कार्मिक प्रबंधन प्रक्रिया है जो कर्मचारी के श्रेष्ठ कार्य, समर्पण और योग्यता को मान्यता देने हेतु की जाती है। यह कर्मचारियों हेतु एक सशक्त अभिप्रेरक है जो उन्हें बेहतर प्रदर्शन हेतु प्रोत्साहित करती है। इसके विपरीत, अनुशासनात्मक कार्रवाई त्रुटिपूर्ण व्यवहार हेतु दंड देने से संबंधित है। वरिष्ठता का सिद्धांत सरल और स्पष्ट होता है क्योंकि यह केवल सेवा की अवधि पर आधारित है। योग्यता का सिद्धांत श्रेष्ठतम प्रतिभा को चुनता है, यद्यपि इसे लागू करते समय निष्पक्षता और वस्तुनिष्ठता बनाए रखना प्रबंधन हेतु एक बड़ी चुनौती है।

128. (B) यह कर्मचारी को कार्य करते हुए सीखने की अनुमति देता है।
कार्य-स्थल पर प्रशिक्षण की सबसे बड़ी विशेषता इसकी व्यावहारिकता है। कर्मचारी वास्तविक उपकरणों, फाइलों और समस्याओं के साथ प्रत्यक्ष कार्य करते हुए कौशल अर्जित करता है। इससे उसे सैद्धांतिक ज्ञान और व्यावहारिक अनुप्रयोग के बीच के संबंध को समझने में सुगमता होती है। यह संगठन हेतु कम व्यय वाली विधि है क्योंकि इसके लिए किसी पृथक बुनियादी ढांचे या यात्रा व्यय की आवश्यकता नहीं होती। इसके अतिरिक्त, कर्मचारी प्रशिक्षण के दौरान भी संगठन की उत्पादकता में अपना निरंतर योगदान देना जारी रखता है, जो इसे अत्यंत कुशल बनाता है।

129. (B) एल्विन गोल्डनर
समाजशास्त्री एल्विन गोल्डनर ने अपने औद्योगिक अध्ययन के आधार पर नौकरशाही के व्यवहार का सूक्ष्म विश्लेषण किया। उन्होंने नौकरशाही को दो प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया: दंड-केंद्रित और प्रतिनिधि। दंड-केंद्रित नौकरशाही वह है जहाँ नियम ऊपर से आरोपित किए जाते हैं और उनके उल्लंघन पर कठोर दंड दिया जाता है, जिससे तनाव उत्पन्न होता है। इसके विपरीत, प्रतिनिधि नौकरशाही में नियमों को विशेषज्ञों द्वारा निर्मित किया जाता है और उन्हें कर्मचारियों की सहमति हेतु लागू किया जाता है। गोल्डनर के इस विश्लेषण ने संगठनात्मक व्यवहार में नियमों की स्वीकृति के महत्व को रेखांकित किया।

130. (A) P-3, Q-4, R-1, S-2
मद-वार बजट व्यय की विशिष्ट मदों पर कठोर वित्तीय नियंत्रण रखने हेतु निर्मित किया जाता है। निष्पादन बजट का उद्देश्य वित्तीय व्ययों को उनके द्वारा प्राप्त भौतिक परिणामों और उपलब्धियों के साथ संयुक्त करना है। शून्य-आधारित बजटिंग में प्रत्येक वर्ष सभी कार्यक्रमों की आवश्यकता का नए सिरे से मूल्यांकन और औचित्य सिद्ध किया जाता है। नियोजन, कार्यक्रम निर्धारण, बजट प्रणाली एक आधुनिक तकनीक है जो संगठन के दीर्घकालिक नियोजन और बजट के बीच गहरा अंतर्संबंध स्थापित करती है। ये सभी तकनीकें बजटीय पारदर्शिता और प्रबंधन दक्षता को बढ़ाने के विभिन्न प्रयास हैं।

131. (C) राजनीतिक कारणों से बार-बार और मनमाने स्थानांतरण।
सिविल सेवा की राजनीतिक तटस्थता का अर्थ है कि लोक सेवक किसी भी राजनीतिक दल के प्रति वफादारी के बिना केवल जनहित और कानून के प्रति प्रतिबद्ध रहें। यद्यपि, जब राजनीतिक नेतृत्व अपनी इच्छानुसार अधिकारियों के बार-बार और अनुचित स्थानांतरण करता है, तो यह तटस्थता संकट में पड़ जाती है। यह अधिकारियों को भयभीत करने या उन्हें विशिष्ट विचारधारा के अनुकूल बनाने का एक उपकरण बन जाता है। ऐसे मनमाने स्थानांतरण प्रशासनिक स्थिरता को क्षति पहुँचाते हैं और लोक सेवकों के पेशेवर मनोबल को गिराते हैं, जिससे अंततः पूरी शासन व्यवस्था प्रभावित होती है।

132. (D) प्रभावी संचार को रोकती है या उसमें व्यवधान डालती है।
संचार में बाधा का अर्थ है कोई भी ऐसा कारक जो सूचना के स्पष्ट प्रवाह को बाधित करता है या संदेश के अर्थ को विकृत कर देता है। ये बाधाएं भौतिक हो सकती हैं, जैसे तकनीकी त्रुटि, या मानवीय हो सकती हैं, जैसे भाषा की अस्पष्टता, सांस्कृतिक भिन्नता या पूर्वग्रह। जब संचार में बाधा आती है, तो प्रेषक का मूल विचार प्राप्तकर्ता तक सटीक ढंग से नहीं पहुँच पाता, जिससे गलतफहमियां उत्पन्न होती हैं और संगठन की

Downloaded from www.pdf.tube

और नवीन सक्षमता को हतोत्साहित करती है, जिससे संगठन की गतिशीलता प्रभावित होती है।

167. (D) कर्मचारियों को उत्पीड़ित करना।
अनुशासनात्मक कार्रवाई का उद्देश्य कभी भी किसी कर्मचारी का व्यक्तिगत उत्पीड़न करना या उसे मानसिक पीड़ा पहुँचाना नहीं होता। इसके विपरीत, इसका प्राथमिक लक्ष्य संगठन में अनुशासन और कार्य के मानकों को अक्षुण्ण बनाए रखना है। यह एक सुधारात्मक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य कर्मचारी को उसके त्रुटिपूर्ण आचरण का बोध कराना और उसे भविष्य में सुधार हेतु प्रेरित करना है। इसके अतिरिक्त, यह अन्य कर्मचारियों हेतु एक उदाहरण के रूप में भी कार्य करती है ताकि वे नियमों का उल्लंघन न करें। एक स्वस्थ प्रशासनिक व्यवस्था में अनुशासन का प्रयोग केवल न्यायसंगत और विधिक प्रक्रियाओं के अनुपालन के साथ ही किया जाता है।

168. (A) नियम बिना किसी व्यक्तिगत पक्षपात के लागू होने चाहिए।
वेबर की नौकरशाही में 'निर्वैयक्तिकता' का अर्थ है कि प्रशासन भावनाओं, व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों या सामाजिक संबंधों से पूर्णतः मुक्त होना चाहिए। लोक सेवकों को अपने आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन करते समय सभी नागरिकों और स्थितियों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, जैसा कि लिखित नियमों में निर्धारित है। यहाँ व्यक्ति का महत्व नहीं, बल्कि उसके पद और विधिक नियमों का महत्व होता है। यह गुण यह सुनिश्चित करता है कि निर्णय प्रक्रिया में निष्पक्षता बनी रहे और भाई-भतीजावाद या भ्रष्टाचार की संभावना न्यून हो। निर्वैयक्तिकता ही नौकरशाही को एक औपचारिक और विश्वसनीय संस्थागत ढांचा प्रदान करती है।

169. (C) सर्वोत्तम कार्ययोजना चुनने की प्रक्रिया का मार्गदर्शन करना।
निर्णय लेना नेतृत्व का एक अनिवार्य और केंद्रीय कार्य है। एक नेता की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह कितनी कुशलता से उपलब्ध विकल्पों का विश्लेषण करता है और संगठन हेतु सर्वाधिक लाभदायक मार्ग का चयन करता है। नेता की भूमिका केवल निर्णय लेना ही नहीं, बल्कि उस प्रक्रिया में अपनी टीम को सम्मिलित करना और उन्हें सही दिशा प्रदर्शित करना भी है। उसे दूरदर्शिता और साहस के साथ उन विकल्पों का चयन करना होता है जो दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक हों। प्रभावी नेतृत्व निर्णय लेने की प्रक्रिया में स्पष्टता और विश्वास जागृत करता है, जो क्रियान्वयन को सफल बनाता है।

170. (B) केवल 2 और 3
कर्मचारी-नियोक्ता संबंधों का मूल उद्देश्य संगठन में शांति और सहयोग का वातावरण निर्मित करना है, न कि संघर्ष को बढ़ावा देना। सामूहिक सौदेबाजी एक महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जहाँ कर्मचारी और प्रबंधन मिलकर सेवा शर्तों पर सहमति बनाते हैं। जब कर्मचारियों की व्यथाओं को समय पर सुना जाता है और उनके हितों का ध्यान रखा जाता है, तो उनके बीच पारस्परिक विश्वास में वृद्धि होती है। यह विश्वास ही उच्च मनोबल और अंततः उत्पादकता में वृद्धि का कारण बनता है। इसके विपरीत, संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र जैसे मंचों का मुख्य उद्देश्य विवादों का बातचीत के माध्यम से समाधान करना होता है, जो संघर्षों को न्यूनतम करते हैं।

171. (B) अमेरिकी रक्षा विभाग में।
नियोजन, कार्यक्रम निर्धारण, बजट प्रणाली की शुरुआत 1960 के दशक में अमेरिकी रक्षा विभाग में हुई थी। यह एक क्रांतिकारी बजटीय तकनीक थी जिसने बजट निर्माण को दीर्घकालिक नियोजन और रणनीतिक उद्देश्यों के साथ संयुक्त किया। इसमें केवल एक वर्ष के व्यय के बजाय भविष्य के परिणामों और लागत-लाभ विश्लेषण पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसकी सफलता के पश्चात, इसे अन्य संघीय विभागों में भी लागू किया गया। यद्यपि बाद में इसकी जटिलता के कारण इसमें परिवर्तन किए गए, किंतु इसने आधुनिक बजटीय चिंतन और प्रदर्शन मूल्यांकन को गहराई से प्रभावित किया है।

172. (B) अक्षमता, विलंब, लापरवाही और प्रशासनिक उदासीनता।
ओम्बुड्समैन का अधिकार क्षेत्र केवल भ्रष्टाचार तक सीमित नहीं है, बल्कि वह 'कुप्रशासन' के व्यापक दायरे की भी सूक्ष्म जांच करता है। इसमें लोक सेवकों द्वारा की गई ऐसी कोई भी त्रुटि सम्मिलित है जिससे नागरिक के विधिक अधिकारों का हनन होता है या उसे अनावश्यक कष्ट पहुँचता है। विलंब के कारण किसी कार्य का न होना, फाइलों का लापरवाही से लुप्त हो जाना, या अधिकारियों का अशिष्ट और उदासीन व्यवहार कुप्रशासन के स्पष्ट उदाहरण हैं। ओम्बुड्समैन यह सुनिश्चित करता है कि प्रशासन केवल कानून का पालन ही न करे, बल्कि वह नागरिकों के प्रति संवेदनशील, तत्पर और पूर्णतः निष्पक्ष भी बना रहे।

173. (C) मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व
संसदीय व्यवस्था में लोक सेवकों की अनामिकता मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व के सिद्धांत का एक अनिवार्य परिणाम है। चूँकि मंत्री अपने विभाग की प्रत्येक नीति और कार्य हेतु व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से संसद के प्रति जवाबदेह होते हैं, इसलिए लोक सेवक पर्दे के पीछे रहकर कार्य करते हैं। उनकी भूमिका केवल मंत्री को विशेषज्ञ परामर्श देने और निर्णयों को क्रियान्वित करने तक सीमित होती है। यदि कोई नीति विफल होती है, तो उसकी आलोचना मंत्री की होती है, न कि उसे निर्मित करने वाले अधिकारियों की। यह व्यवस्था लोक सेवकों को राजनीतिक प्रतिशोध से सुरक्षा प्रदान करती है और प्रशासनिक व्यावसायिकता अक्षुण्ण बनाए रखती है।

174. (D) सभी के लिए खुली प्रतिस्पर्धी परीक्षाएं
सीधी भर्ती कार्मिक प्रशासन की वह पद्धति है जिसमें संगठन के बाहर की नवीन प्रतिभाओं को प्रवेश का अवसर प्रदान किया जाता है। इसका सबसे सामान्य और पारदर्शी माध्यम सभी पात्र नागरिकों हेतु खुली प्रतिस्पर्धी परीक्षाएं हैं। ये परीक्षाएं लिखित परीक्षा, साक्षात्कार और कभी-कभी शारीरिक परीक्षण के माध्यम से उम्मीदवारों की योग्यता और क्षमता का निष्पक्ष मूल्यांकन करती हैं। सीधी भर्ती से संगठन में नवीन दृष्टिकोण, ऊर्जा और विशेषज्ञता का संचार होता है। यह लोकतांत्रिक समानता के सिद्धांत का अनुपालन करती है, जहाँ वांछित

NODIA

लालफीताशाही, लक्ष्य विस्थापन, नवाचार का विरोध, संवेदनहीनता और सत्ता का अनावश्यक मोह सम्मिलित है। ये विकृतियां संगठन की कार्यक्षमता को नष्ट कर देती हैं और उसे जनता की आवश्यकताओं के प्रति उदासीन बना देती हैं। विकृति शब्द का प्रयोग यहाँ इसलिए किया गया है क्योंकि ये स्थितियां एक स्वस्थ और कुशल प्रशासन के मार्ग में व्याधि की भांति बाधा उत्पन्न करती हैं, जिन्हें व्यापक सुधार की आवश्यकता होती है।

142. (D) लोकतांत्रिक शैली
लोकतांत्रिक नेतृत्व शैली, जिसे सहभागितापूर्ण शैली भी कहा जाता है, इस विश्वास पर आधारित है कि निर्णय लेने में अधीनस्थों की राय सम्मिलित करने से श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त होते हैं। इस शैली में नेता अपने कर्मचारियों के साथ सूचनाएं साझा करता है और उन्हें सुझाव देने हेतु प्रोत्साहित करता है। इससे कर्मचारियों में संगठन के प्रति अपनेपन और जिम्मेदारी की भावना जागृत होती है। यद्यपि अंतिम निर्णय नेता का होता है, किंतु परामर्श की प्रक्रिया से टीम का मनोबल ऊँचा रहता है और निर्णयों का क्रियान्वयन अधिक प्रभावी ढंग से होता है क्योंकि सभी उसमें स्वयं को सम्मिलित पाते हैं।

143. (A) सर्वसम्मति-उन्मुख निर्णय प्रक्रिया।
सुशासन का एक प्रमुख तत्व यह सुनिश्चित करना है कि समाज के विभिन्न वर्गों के हितों के बीच समन्वय हो और निर्णय लेते समय व्यापक सर्वसम्मति निर्मित करने का प्रयास किया जाए। यह दृष्टिकोण प्रशासन को अधिक न्यायसंगत और स्वीकार्य बनाता है। सर्वसम्मति-उन्मुख होने का अर्थ यह नहीं है कि सभी एक मत हों, बल्कि यह है कि अल्पसंख्यकों और दुर्बल वर्गों की वाणी को भी सुना जाए। यह समावेशी विकास की दिशा में एक कदम है, जो प्रशासन में टकराव को कम करता है और सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देता है, जो सुशासन का मूल उद्देश्य है।

144. (B) अधिनियम की धारा 8।
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत यद्यपि पारदर्शिता मुख्य नियम है, किंतु कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में गोपनीयता बनाए रखना भी आवश्यक माना गया है। अधिनियम की धारा 8 उन विषयों की सूची प्रदान करती है जिन्हें सार्वजनिक प्रकटीकरण से छूट प्रदान की गई है। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ संबंध, व्यक्तिगत गोपनीयता, वाणिज्यिक गोपनीयता और जांच प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली सूचनाएं सम्मिलित हैं। जन सूचना अधिकारी इन श्रेणियों के अंतर्गत आने वाली सूचनाओं को देने से मना कर सकता है, बशर्ते कि व्यापक जनहित में उनका खुलासा आवश्यक न हो।

145. (B) 3, 4, 2, 1
भारत में भ्रष्टाचार विरोधी तंत्र का विकास चरणबद्ध तरीके से हुआ। 1962 में भ्रष्टाचार रोकने हेतु संथानम समिति का गठन किया गया। इसके पश्चात 1963 में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना हुई। 1964 में संथानम समिति की सिफारिशों के आधार पर केंद्रीय सतर्कता आयोग निर्मित किया गया। अंततः, एक दीर्घकालिक जन आंदोलन और विधायी प्रक्रिया के पश्चात 2013 में लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम पारित किया गया। यह क्रम भारत में भ्रष्टाचार के विरुद्ध बढ़ती विधिक और संस्थागत गंभीरता को दर्शाता है, जिसका परम लक्ष्य सार्वजनिक जीवन में शुचिता लाना है।

146. (A) आत्म-सम्मान, मान्यता और विकास।
पदोन्नति केवल वेतन वृद्धि का साधन नहीं है, बल्कि यह कर्मचारी के व्यावसायिक जीवन में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है। यह कर्मचारी को संगठन में उच्च पद और प्रतिष्ठा प्रदान करती है, जिससे उसका आत्म-सम्मान और आत्मविश्वास बढ़ता है। यह उसकी कार्य क्षमता और समर्पण की आधिकारिक पुष्टि होती है, जो उसे भविष्य में और अधिक उत्तरदायित्व स्वीकार करने हेतु तैयार करती है। अब्राहम मास्लो के सिद्धांत के अनुसार, पदोन्नति व्यक्ति की सम्मान और आत्म-विकास की उच्च स्तरीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करती है, जो उसे निरंतर सक्रिय बनाए रखती है।

147. (C) A सत्य है लेकिन आर असत्य है।
संसदीय लोकतंत्र में मंत्री और लोक सेवक के बीच का संबंध व्यक्तिगत नहीं, बल्कि मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर आधारित होता है। मंत्री अपने विभाग के समस्त कार्यों और निर्णयों हेतु संसद के प्रति प्रत्यक्ष और अंतिम रूप से जवाबदेह होता है। दूसरी ओर, लोक सेवक सीधे संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होते; वे केवल अपने मंत्री के प्रति जवाबदेह होते हैं। लोक सेवक अनामिक रहकर विशेषज्ञ सलाह प्रदान करते हैं, जबकि मंत्री जनता के प्रतिनिधि के रूप में उस सलाह के आधार पर निर्णय लेने का संवैधानिक उत्तरदायित्व निर्वहन करते हैं।

148. (A) भर्ती, विकास और अभिप्रेरणा से संबंधित गतिविधियाँ।
कार्मिक प्रशासन संगठन में मानव संसाधन के प्रभावी प्रबंधन की एक व्यापक प्रक्रिया है। इसमें न केवल नवीन प्रतिभाओं की खोज और भर्ती सम्मिलित है, बल्कि उनके निरंतर प्रशिक्षण और कौशल विकास पर भी ध्यान केंद्रित किया जाता है ताकि वे बदलती चुनौतियों का सामना कर सकें। इसके अतिरिक्त, कर्मचारियों को संतुष्ट और ऊर्जावान बनाए रखने हेतु अभिप्रेरणा, पदोन्नति और कल्याणकारी योजनाएं भी इसी का अंग हैं। इसका मूल उद्देश्य एक ऐसा कार्यबल तैयार करना और उसे बनाए रखना है जो संगठनात्मक लक्ष्यों को कुशलता और पूर्ण समर्पण के साथ प्राप्त करने में सक्षम हो।

149. (B) सांस्कृतिक संदर्भ और शक्ति संबंधों की भूमिका।
मिशेल क्रोज़ियर ने नौकरशाही का विश्लेषण करते हुए यह तर्क दिया कि संगठन केवल नियमों का समूह नहीं है, बल्कि यह शक्ति के आपसी संबंधों और सांस्कृतिक मूल्यों का भी परिणाम होता है। उनके अनुसार, नौकरशाही एक ऐसा तंत्र है जो अपनी त्रुटियों से सीखने में असमर्थ होता है क्योंकि अनिश्चितता के क्षेत्र शक्ति के स्रोत बन जाते हैं। क्रोज़ियर ने फ्रांसीसी संगठनों के अपने अध्ययन में प्रदर्शित किया कि कैसे सांस्कृतिक प्रवृत्तियां नौकरशाही की संरचना और व्यवहार को प्रभावित करती हैं। उन्होंने नियमों की जकड़न को शक्ति संघर्षों और प्रशासनिक अक्षमता के एक दुष्चक्र के रूप में वर्णित किया।

Click Here to Buy book on Amazon

पूर्णतः अनुचित माना जाता है क्योंकि यह समानता और न्याय के आदर्शों के विरुद्ध है।

183. (A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।
संसदीय व्यवस्था में विभाग का नेतृत्व दो स्तरों पर होता है। मंत्री निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में विभाग का राजनीतिक प्रमुख होता है, जो नीतिगत दिशा निर्धारित करता है और संसद के प्रति पूर्णतः जवाबदेह होता है। दूसरी ओर, सचिव या वरिष्ठ लोक सेवक विभाग का प्रशासनिक प्रमुख होता है, जो विभाग के दैनिक कार्यों, कर्मचारियों के प्रबंधन और नीतियों के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी वहन करता है। ये दोनों मिलकर प्रशासन की गति सुनिश्चित करते हैं। मंत्री का राजनीतिक विजन और लोक सेवक की प्रशासनिक विशेषज्ञता का समन्वय ही सरकार की सफलता सुनिश्चित करता है और लोक कल्याण के लक्ष्यों को प्राप्त करता है।

184. (A) अत्यधिक कुशल, अभिप्रेरित और स्वतंत्र रूप से कार्य करने में सक्षम।
अहस्तक्षेपकारी नेतृत्व शैली तभी प्रभावी सिद्ध होती है जब अनुयायी अपने क्षेत्र में पूर्णतः विशेषज्ञ हों और उन्हें किसी निरंतर पर्यवेक्षण या दिशा-निर्देश की आवश्यकता न हो। ऐसी स्थिति में नेता हस्तक्षेप न करके उन्हें अपनी रचनात्मकता और कौशल प्रदर्शित करने का पूर्ण अवसर प्रदान करता है। यह शैली शोधकर्ताओं, वैज्ञानिकों और उच्च पेशेवर दलों हेतु उपयुक्त है जहाँ कर्मचारी स्वयं के लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। यद्यपि, यदि टीम में अनुभव या प्रेरणा का अभाव हो, तो नेतृत्व की यह शैली अनुशासनहीनता और लक्ष्यों के प्रति भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर सकती है, जिससे परिणाम प्रभावित होते हैं।

185. (C) सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने के लिए एक सहयोगात्मक प्रयास।
सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल उदारीकरण के पश्चात की एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवधारणा है। यह इस विचार पर आधारित है कि बुनियादी ढांचे के निर्माण और सेवाओं के वितरण में सरकार के पास संसाधनों और तकनीकी विशेषज्ञता की कमी हो सकती है। इस मॉडल के माध्यम से सरकार निजी क्षेत्र की पूंजी, दक्षता और नवाचार का उपयोग करती है, जबकि स्वयं नियामक और जनकल्याण के संरक्षक की भूमिका का निर्वहन करती है। यह न तो पूर्ण निजीकरण है और न ही पूर्ण सरकारी नियंत्रण, बल्कि दोनों क्षेत्रों की शक्तियों को सम्मिलित कर जनहित में कार्य करने का एक सहयोगात्मक और आधुनिक प्रशासनिक मार्ग है।

186. (A) चर्चा, अनुदानों पर मतदान और विनियोग विधेयकों को पारित करना।
लोकतंत्र में सरकार के वित्त पर विधायिका का नियंत्रण एक सर्वोच्च संवैधानिक सिद्धांत है। बजट प्रस्तुत होने के पश्चात संसद में उस पर विस्तृत चर्चा होती है, जहाँ जनप्रतिनिधि सरकार की नीतियों और व्ययों की गहन समीक्षा करते हैं। इसके पश्चात विभिन्न मंत्रालयों की अनुदान की मांगों पर मतदान होता है, जिसमें कटौती प्रस्तावों के माध्यम से असहमति व्यक्त की जा सकती है। अंत में, विनियोग विधेयक पारित होने पर ही सरकार को संचित निधि से धन आहरण का विधिक अधिकार प्राप्त होता है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि सार्वजनिक धन का प्रत्येक अंश जनता के प्रतिनिधियों की अनुमति से ही व्यय हो।

187. (D) प्रशासन में भ्रष्टाचार।
भारत में भ्रष्टाचार की समस्या का अध्ययन करने और उसे रोकने हेतु 1962 में के. संथानम की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने प्रशासन में ईमानदारी अक्षुण्ण रखने हेतु क्रांतिकारी सिफारिशें प्रदान कीं, जिनमें केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी। समिति ने भ्रष्टाचार के कारणों, जैसे अत्यधिक विवेकाधिकार और जटिल प्रक्रियाओं का विश्लेषण किया और उन्हें न्यून करने के सुझाव दिए। संथानम समिति की रिपोर्ट आज भी भारत में भ्रष्टाचार विरोधी नीतियों और संस्थागत ढांचे के निर्माण हेतु एक आधारभूत और दिशा-निर्देशक प्रलेख मानी जाती है।

188. (B) लापरवाही के कारण किसी अधिकारी द्वारा फाइल खो देना।
कुप्रशासन का अर्थ प्रशासन की वह स्थिति है जहाँ कार्यों को नियमों, तत्परता और ईमानदारी के साथ निष्पादित नहीं किया जाता। यदि कोई अधिकारी अपनी लापरवाही या उदासीनता के कारण किसी महत्वपूर्ण फाइल को लुप्त कर देता है, तो यह कुप्रशासन का एक स्पष्ट उदाहरण है क्योंकि इससे निर्णय प्रक्रिया बाधित होती है और नागरिक को अनावश्यक असुविधा होती है। यह भ्रष्टाचार से भिन्न हो सकता है क्योंकि इसमें व्यक्तिगत लाभ सम्मिलित नहीं होता, किंतु यह प्रशासनिक अक्षमता और उत्तरदायित्व के अभाव को दर्शाता है। कुप्रशासन जनता के विश्वास को दुर्बल करता है और इसे सुधारने हेतु ओम्बुड्समैन जैसी संस्थाएं कार्य करती हैं।

189. (C) दोनों तत्वों को मिलाने वाला एक संकर मॉडल।
प्रशिक्षण की सैंडविच पद्धति एक अनूठी संरचना है जो सैद्धांतिक शिक्षा और व्यावहारिक अनुभव को आपस में संयुक्त करती है। इसमें प्रशिक्षु पहले कुछ समय किसी अकादमी में सैद्धांतिक ज्ञान प्राप्त करता है, फिर उसे वास्तविक कार्य अनुभव हेतु कुछ समय तक 'क्षेत्र' में तैनात किया जाता है। इसके पश्चात वह पुनः अकादमी लौटता है ताकि वह अपने व्यावहारिक अनुभवों को सिद्धांतों के साथ जोड़ सके और अपनी शंकाओं का तार्किक समाधान प्राप्त कर सके। यह चक्र प्रशिक्षण को अधिक प्रभावी और संतुलित बनाता है, जिससे लोक सेवक अकादमिक और व्यावहारिक दोनों मोर्चों पर पूरी तरह तैयार होकर जनता की सेवा कर पाते हैं।

190. (B) P-3, Q-4, R-1, S-2
भर्ती की प्रक्रिया में लिखित परीक्षा और साक्षात्कार जैसे उपकरण उम्मीदवारों की योग्यता के परीक्षण हेतु उपयोग किए जाते हैं। प्रशिक्षण में मामला अध्ययन विधि प्रशिक्षुओं की विश्लेषणात्मक क्षमता विकसित करने हेतु अपनाई जाती है। निष्पादन मूल्यांकन हेतु भारत में वार्षिक कार्य निष्पादन

NODIA

योग्यता रखने वाला कोई भी व्यक्ति लोक सेवा का अंग बनने हेतु आवेदन कर सकता है।

175. (A) कार्यस्थल पर सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारक।
एल्टन मेयो द्वारा किए गए हॉथोर्न प्रयोगों ने शास्त्रीय प्रबंधकीय विचारधारा को चुनौती प्रदान की, जो मनुष्य को केवल एक 'आर्थिक प्राणी' मानती थी। इन प्रयोगों से यह सिद्ध हुआ कि कार्यस्थल पर प्रकाश या वेतन जैसे भौतिक कारकों से अधिक महत्वपूर्ण सामाजिक संबंध, समूह की भावना और मनोवैज्ञानिक संतुष्टि होती है। कर्मचारियों की उत्पादकता तब बढ़ती है जब उन्हें प्रबंधन द्वारा महत्व दिया जाता है और वे एक अनौपचारिक सामाजिक समूह का हिस्सा अनुभव करते हैं। इन निष्कर्षों ने 'मानवीय संबंध आंदोलन' की आधारशिला रखी और संगठन में मानवीय तत्व के महत्व को वैश्विक स्तर पर मान्यता प्रदान की।

176. (B) एक लिखित ज्ञापन, ईमेल या बातचीत।
संचार प्रक्रिया में 'माध्यम' वह पथ या साधन है जिसके द्वारा प्रेषक अपना संदेश प्राप्तकर्ता तक पहुँचाता है। यह माध्यम मौखिक हो सकता है जैसे आमने-सामने की बातचीत या दूरभाष, और लिखित भी हो सकता है जैसे पत्र, ज्ञापन, ईमेल या आधिकारिक रिपोर्ट। माध्यम का चयन संदेश की प्रकृति, तात्कालिकता और प्रेषक-प्राप्तकर्ता के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। एक सटीक माध्यम का चयन संदेश की स्पष्टता और उसके प्रभाव को सुनिश्चित करने हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि त्रुटिपूर्ण माध्यम संचार प्रक्रिया में गंभीर बाधा उत्पन्न कर सकता है।

177. (B) यथास्थितिवादी और परिवर्तन के प्रति प्रतिरोधी।
विकास प्रशासन का लक्ष्य समाज में सकारात्मक और तीव्र परिवर्तन लाना है, किंतु पारंपरिक नौकरशाही प्रायः अपनी संरचना और स्वभाव में यथास्थितिवादी होती है। नौकरशाह नियमों और स्थापित प्रक्रियाओं के इतने अभ्यस्त हो जाते हैं कि वे किसी भी नवीन विचार या प्रक्रिया में बदलाव का विरोध करते हैं, क्योंकि इसमें अनिश्चितता और जोखिम निहित होता है। यह परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में एक बड़ी बाधा सिद्ध होता है। विकास की चुनौतियों से निपटने हेतु नौकरशाही को अपनी इस सुरक्षात्मक मानसिकता को त्यागकर एक सक्रिय और गतिशील परिवर्तन-अभिकर्ता की भूमिका अपनाने की नितांत आवश्यकता है।

178. (A) वित्तीय जवाबदेही
लेखापरीक्षा लोक प्रशासन में वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करने का एक अनिवार्य और शक्तिशाली उपकरण है। यह सरकारी खातों की सूक्ष्मता से जाँच करने की एक व्यवस्थित प्रक्रिया है, जो यह प्रमाणित करती है कि सार्वजनिक धन का उपयोग विधिक रूप से और स्वीकृत बजट के अनुसार ही किया गया है। लेखापरीक्षा न केवल अनियमितताओं और भ्रष्टाचार को उजागर करती है, बल्कि यह भविष्य में संसाधनों के बेहतर उपयोग हेतु महत्वपूर्ण सुझाव भी प्रदान करती है। इसके माध्यम से विधायिका कार्यपालिका के वित्तीय व्यवहार पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखती है, जो एक पारदर्शी और उत्तरदायी लोकतंत्र हेतु अनिवार्य शर्त है।

179. (C) सूचना का अधिकार अधिनियम।
नागरिक का 'जानने का अधिकार' लोकतंत्र का एक मौलिक दर्शन है, जो इस विचार पर आधारित है कि जनता ही सर्वोच्च स्वामी है और उसे यह जानने का पूर्ण अधिकार है कि उसकी निर्वाचित सरकार कैसे कार्य कर रही है। यही विचार सूचना का अधिकार अधिनियम का आधार बना। यह अधिनियम प्रशासन की गोपनीयता को समाप्त कर उसे जनता के प्रति पारदर्शी बनाता है। जब नागरिकों के पास सटीक सूचना होती है, तो वे सरकार को जवाबदेह बना सकते हैं और निर्णय लेने की प्रक्रिया में अधिक प्रभावी ढंग से सम्मिलित हो सकते हैं। यह सशक्त नागरिक और पारदर्शी शासन के बीच एक मजबूत सेतु का कार्य करता है।

180. (D) प्रधानमंत्री, मंत्री और संसद सदस्य।
लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के अंतर्गत स्थापित लोकपाल का अधिकार क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। इसमें भ्रष्टाचार के विरुद्ध जांच के दायरे में भारत के प्रधानमंत्री, केंद्र सरकार के समस्त मंत्री, संसद के सदस्य और केंद्र सरकार के सभी श्रेणियों के अधिकारी व कर्मचारी सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त, उन सभी संस्थाओं के प्रमुख और कर्मचारी भी इसके दायरे में आते हैं जो पूर्णतः या आंशिक रूप से सरकार द्वारा वित्तपोषित हैं। यह व्यापक अधिकार क्षेत्र यह सुनिश्चित करता है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष में कोई भी उच्च पद जवाबदेही से ऊपर न रहे, जिससे प्रशासनिक शुचिता बनी रहे।

181. (C) मनोबल के लिए एक नकारात्मक कारक।
पदोन्नति का अर्थ सामान्यतः उच्च पदनाम के साथ-साथ वेतन और सुविधाओं में वृद्धि होना है। जब किसी कर्मचारी को केवल उच्च पद का उत्तरदायित्व प्रदान कर दिया जाता है किंतु उसके वेतन में कोई वृद्धि नहीं की जाती, तो इसे 'शुष्क पदोन्नति' कहा जाता है। यद्यपि इससे कर्मचारी की प्रतिष्ठा में किंचित वृद्धि हो सकती है, किंतु आर्थिक लाभ के अभाव में यह अक्सर असंतोष का कारण बनती है। कर्मचारी को अनुभव होता है कि उस पर कार्य का भार तो बढ़ा दिया गया किंतु उसका उचित प्रतिफल नहीं मिला। इसलिए, ऐसी पदोन्नति को कर्मचारी के दीर्घकालिक मनोबल और प्रेरणा हेतु एक नकारात्मक कारक माना जाता है।

182. (B) विशेषाधिकार प्राप्त जन्म या सामाजिक वर्ग।
एफ.एम. मार्क्स के अनुसार जातीय नौकरशाही वह प्रणाली है जहाँ सरकारी पदों पर भर्ती हेतु व्यक्तिगत योग्यता या परीक्षा के स्थान पर जन्म, कुल या सामाजिक प्रतिष्ठा को आधार माना जाता है। इस व्यवस्था में प्रशासनिक पद समाज के एक विशिष्ट अभिजात वर्ग हेतु आरक्षित होते हैं, जो अपनी स्थिति का उपयोग अपने वर्ग के हितों की रक्षा हेतु करते हैं। यह प्रणाली सामाजिक गतिशीलता को अवरुद्ध करती है और समाज के एक बड़े भाग को शासन प्रक्रिया से बहिष्कृत रखती है। आधुनिक लोकतांत्रिक युग में इस प्रकार की नौकरशाही को

Downloaded from www.pdf.tube

उम्मीदवारों की क्षमता के आधार पर हों। भर्ती के अतिरिक्त, आयोग पदोन्नति, स्थानांतरण और अनुशासनात्मक मामलों पर भी सरकार को विशेषज्ञ परामर्श प्रदान करता है। इसकी स्वतंत्रता प्रशासन में व्यावसायिकता और स्थिरता बनाए रखने हेतु अनिवार्य है, जिससे एक सक्षम और तटस्थ कार्यपालिका का निर्माण संभव होता है।

199. (D) नीति निर्माण और कार्यान्वयन के बीच एक बड़ा अंतराल।
विकास योजनाओं की विफलता का एक बड़ा कारण अक्सर यह होता है कि कागज़ पर निर्मित नीतियां जमीनी वास्तविकता से मेल नहीं खातीं। इसे 'कार्यान्वयन अंतराल' कहा जाता है, जहाँ योजनाकार स्थानीय परिस्थितियों, संसाधनों की कमी और प्रशासनिक सीमाओं की अनदेखी कर देते हैं। जब तक नीति निर्माण और उसे लागू करने वाली एजेंसी के बीच प्रभावी समन्वय नहीं होगा, तब तक श्रेष्ठ विचार भी वांछित परिणाम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त, नौकरशाही की अक्षमता और भ्रष्टाचार भी इस अंतराल को विस्तृत करते हैं। सफल विकास हेतु योजना का व्यावहारिक होना और उसका जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन आवश्यक है।

200. (C) केवल 2 और 3
विकास प्रशासन की प्रकृति पारंपरिक प्रशासन से भिन्न होती है, जिसके लिए नियम-बद्ध कठोरता के स्थान पर एक लचीली और संवेदनशील नौकरशाही की आवश्यकता होती है जो बदलती परिस्थितियों के अनुकूल स्वयं को ढाल सके। कठोरता विकास लक्ष्यों में बाधक बनती है और नवाचार को अवरुद्ध करती है। साथ ही, भ्रष्टाचार विकास के मार्ग में सबसे बड़ा अवरोधक है क्योंकि यह संसाधनों को लक्षित लाभार्थियों तक पहुँचने से पूर्व ही नष्ट कर देता है। अतः विकास की सफलता हेतु प्रशासनिक लचीलापन और भ्रष्टाचार-मुक्त वातावरण दोनों ही अनिवार्य हैं। यह सुनिश्चित करता है कि योजनाओं का लाभ न्यायसंगत तरीके से समाज को प्राप्त हो।

201. (C) व्यय कानून और नियमों के अनुरूप है।
लेखापरीक्षा में वैधता का सिद्धांत यह सुनिश्चित करने पर केंद्रित है कि सरकार द्वारा किया गया प्रत्येक वित्तीय लेनदेन स्थापित कानूनों, नियमों और विधिक प्रक्रियाओं के पूर्णतः अनुरूप है। यह जाँचना परीक्षक का प्राथमिक कर्तव्य है कि क्या व्यय करने वाले अधिकारी के पास उस धन को व्यय करने का विधिक अधिकार था और क्या विधायिका द्वारा स्वीकृत सीमा का पालन किया गया है। यह वित्तीय अनुशासन बनाए रखने की एक बुनियादी प्रक्रिया है जो मनमाने ढंग से धन व्यय करने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाती है। वैधता की पुष्टि के बिना सार्वजनिक धन के उपयोग को अनियमित माना जाता है, जिससे जवाबदेही सुनिश्चित होती है।

202. (A) कार्यपालिका द्वारा अन्याय और कुप्रशासन।
ओम्बुड्समैन की संस्था का मूल दर्शन नागरिक को विशाल और कभी-कभी दमनकारी सरकारी मशीनरी के विरुद्ध एक प्रभावी मंच प्रदान करना है। आधुनिक शासन में कार्यपालिका के पास व्यापक शक्तियां होती हैं, जिनका दुरुपयोग कुप्रशासन, पक्षपात या अनुचित विलंब के रूप में हो सकता है। ओम्बुड्समैन एक स्वतंत्र मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है जो जनता की शिकायतों की सूक्ष्म जांच करता है और प्रशासन की त्रुटियों को उजागर करता है। यह संस्था सुनिश्चित करती है कि आम नागरिक को सरकारी अधिकारियों की मनमानी के विरुद्ध न्याय प्राप्त हो सके, जिससे लोकतंत्र में 'विधि के शासन' और मानवीय गरिमा की रक्षा होती है।

203. (D) औपचारिक नियमों का अत्यधिक पालन जिससे विलंब होता है।
लालफीताशाही नौकरशाही की वह नकारात्मक विशेषता है जहाँ नियमों, प्रक्रियाओं और कागजी औपचारिकताओं को वास्तविक कार्य या परिणाम से अधिक महत्व प्रदान किया जाता है। इसमें फाइलों के निपटान में अनावश्यक विलंब होता है क्योंकि प्रत्येक चरण पर कठोर और कभी-कभी निरर्थक नियमों का पालन करना अनिवार्य माना जाता है। यह प्रशासनिक दक्षता को न्यून करता है और जनता हेतु मानसिक तथा वित्तीय बोझ बन जाता है। लालफीताशाही अक्सर भ्रष्टाचार को भी जन्म देती है क्योंकि लोग विलंब से बचने हेतु अनैतिक रास्तों का चयन करने लगते हैं। यह सुशासन और त्वरित सेवा वितरण के मार्ग में एक बड़ी बाधा है।

204. (B) साझा उद्देश्य और स्पष्ट संचार।
उच्च मनोबल के निर्माण हेतु यह अनिवार्य है कि संगठन के समस्त सदस्यों को यह स्पष्ट हो कि उनके कार्य का अंतिम लक्ष्य क्या है और वह संगठन हेतु क्यों महत्वपूर्ण है। जब कर्मचारियों और प्रबंधन के बीच संवाद खुला, पारदर्शी और निरंतर होता है, तो भ्रांतियां दूर होती हैं और विश्वास का वातावरण निर्मित होता है। साझा उद्देश्य की भावना कर्मचारियों में एकता और टीम वर्क को प्रोत्साहित करती है। जब उन्हें अनुभव होता है कि उनकी वाणी सुनी जा रही है और वे निर्णय प्रक्रिया का अंग हैं, तो उनका मनोबल स्वतः ही बढ़ जाता है, जिससे उत्पादकता और कार्य संतुष्टि में निरंतर वृद्धि होती है।

205. (B) 2, 1, 3, 4
भर्ती की प्रक्रिया एक तार्किक अनुक्रम में संचालित होती है। सर्वप्रथम, संगठन यह निर्धारित करता है कि उसे कितने और किस प्रकार के कर्मचारियों की आवश्यकता है, जिसे रिक्तियों का निर्धारण कहा जाता है। इसके पश्चात, विज्ञापन और अन्य माध्यमों से योग्य उम्मीदवारों को आवेदन हेतु आकर्षित किया जाता है। प्राप्त आवेदनों में से विभिन्न परीक्षाओं और साक्षात्कारों द्वारा सर्वाधिक उपयुक्त व्यक्तियों का चयन किया जाता है। अंत में, चयनित उम्मीदवारों को आधिकारिक रूप से नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाता है और वे सेवा में सम्मिलित होते हैं। यह व्यवस्थित क्रम सुनिश्चित करता है कि संगठन को सटीक प्रतिभा प्राप्त हो सके।

206. (D) बर्खास्तगी भविष्य के सरकारी नियोजन के लिए अयोग्य घोषित कर देती है।
बर्खास्तगी सरकारी सेवा में प्रदान किया जाने वाला सर्वाधिक कठोर और अंतिम दंड है। यह न केवल वर्तमान सेवा को समाप्त करता है, बल्कि उस व्यक्ति पर भविष्य में किसी भी सरकारी पद को धारण करने हेतु स्थायी विधिक प्रतिबंध भी अधिरोपित

NODIA

बल्कि विधिक अधिकार होते हैं। वेबर ने इसे आधुनिक समाज की जटिलताओं को सुलझाने हेतु अनिवार्य माना क्योंकि यह श्रम विभाजन, पदानुक्रम और व्यावसायिकता के माध्यम से उच्चतम स्तर की दक्षता प्रदान करती है। यह एक ऐसी सामाजिक संरचना है जो व्यक्तिगत भावनाओं के ऊपर तर्क और व्यवस्था को प्राथमिकता देती है।

223. (A) सुदृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति और प्रशासनिक प्रतिबद्धता।
विकास प्रशासन को सफल बनाने हेतु केवल श्रेष्ठ नीतियां निर्मित करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनके पीछे एक सुदृढ़ राजनीतिक नेतृत्व की इच्छाशक्ति होनी चाहिए जो संसाधनों को एकत्रित कर सके और बाधाओं को दूर कर सके। इसके साथ ही, नौकरशाही का उन लक्ष्यों के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध होना भी अनिवार्य है। जब प्रशासन नीतियों को केवल एक सरकारी आदेश न मानकर सामाजिक परिवर्तन का मिशन स्वीकार करता है, तभी वांछित परिणाम प्राप्त होते हैं। राजनीतिक और प्रशासनिक विजन के बीच सामंजस्य ही विकास की गति को तीव्र करता है और यह सुनिश्चित करता है कि योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे।

224. (B) सरकारी नीति के प्रति असहमति व्यक्त करना।
कटौती प्रस्ताव संसदीय नियंत्रण का एक सशक्त माध्यम है जिसका उपयोग विपक्षी सदस्य बजट चर्चा के दौरान करते हैं। इसके द्वारा वे किसी विशेष मंत्रालय की अनुदान की मांग में न्यूनता करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। यद्यपि ये प्रस्ताव प्रायः पारित नहीं होते, किंतु इनका मुख्य उद्देश्य विशिष्ट सरकारी नीतियों की आलोचना करना, धन के अपव्यय को उजागर करना और प्रशासन की त्रुटियों की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना होता है। यह सरकार को जवाबदेह बनाने और बजटीय प्रस्तावों पर सूक्ष्म बहस सुनिश्चित करने का एक अत्यंत महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक उपकरण है जो वित्तीय पारदर्शिता को बढ़ावा देता है।

225. (A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
जिस प्रकार शरीर के जीवित रहने हेतु रक्त का निरंतर प्रवाह अनिवार्य है, उसी प्रकार किसी भी संगठन के अस्तित्व और कार्य संचालन हेतु संचार नितांत आवश्यक है। सूचना के अभाव में न तो सटीक निर्णय लिए जा सकते हैं और न ही उन पर क्रियान्वयन किया जा सकता है। संचार ही वह माध्यम है जो संगठन के विभिन्न अंगों को परस्पर जोड़ता है और उनमें प्रभावी समन्वय स्थापित करता है। यह नेतृत्व, अभिप्रेरणा और नियंत्रण हेतु आधार प्रदान करता है। यदि सूचना का प्रवाह अवरुद्ध हो जाए, तो संगठन में भ्रम, निष्क्रियता और अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, जिससे लक्ष्यों की प्राप्ति असंभव होगी।

226. (A) यह सामाजिक-नैतिक निष्पादन और सामुदायिक प्रभाव पर केंद्रित है।
सामाजिक लेखापरीक्षा पारंपरिक वित्तीय लेखापरीक्षा से अत्यंत व्यापक है। जहाँ वित्तीय लेखापरीक्षा केवल व्ययों की वैधता और साक्ष्यों की जाँच करती है, वहीं सामाजिक लेखापरीक्षा यह देखती है कि किसी योजना ने वास्तव में समाज के जीवन में क्या गुणात्मक परिवर्तन लाया। इसमें जनता की प्रत्यक्ष भागीदारी होती है, जो यह प्रमाणित करती है कि कार्य की गुणवत्ता कैसी थी और क्या लाभ वास्तविक पात्रों तक पहुँचा। यह प्रशासन की नैतिक जवाबदेही और सामाजिक जिम्मेदारी का मूल्यांकन करती है। यह प्रक्रिया सरकारी व्यय को मानवीय और सामाजिक मूल्यों की कसौटी पर कसने का एक क्रांतिकारी और पारदर्शी मार्ग है।

227. (B) सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम, 2002
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 को क्रियान्वित करने से पूर्व भारत सरकार ने 2002 में 'सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम' पारित किया था। यद्यपि, वह कानून अपनी अनेक सीमाओं और अस्पष्टताओं के कारण प्रभावी नहीं हो सका और उसे कभी अधिसूचित भी नहीं किया गया। नागरिकों की निरंतर बढ़ती मांगों और व्यापक विमर्श के पश्चात, एक अधिक सशक्त और व्यापक कानून के रूप में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 लाया गया। इस नवीन कानून ने पुराने 2002 के अधिनियम का स्थान लिया और सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया को अधिक सरल, समयबद्ध और दंडात्मक प्रावधानों के साथ सुदृढ़ बनाया, जिससे वास्तविक पारदर्शिता संभव हुई।

228. (D) लोक सेवक
लोक सेवकों को 'स्थायी कार्यपालिका' कहा जाता है क्योंकि वे किसी राजनीतिक दल की विजय या पराजय से अप्रभावित रहकर सेवानिवृत्ति तक अपने पद पर बने रहते हैं। उनसे यह संवैधानिक अपेक्षा की जाती है कि वे राजनीतिक रूप से पूर्णतः तटस्थ रहें, जिसका अर्थ है कि वे किसी भी विचारधारा के प्रति व्यक्तिगत निष्ठा रखने के स्थान पर केवल संविधान और कानून के प्रति वफादार रहें। यह तटस्थता उन्हें वर्तमान सरकार की नीतियों को पूरी ईमानदारी से क्रियान्वित करने और आगामी सरकार को निष्पक्ष परामर्श देने की क्षमता प्रदान करती है। यही गुण शासन व्यवस्था में प्रशासनिक निरंतरता और निष्पक्षता की वास्तविक गारंटी है।

229. (C) मामला अध्ययन
कार्य-बाह्य प्रशिक्षण विधियां वे हैं जहाँ कर्मचारी को उसके नियमित कार्य स्थल से दूर किसी शांत और शैक्षिक वातावरण में प्रशिक्षित किया जाता है। मामला अध्ययन इसका एक प्रमुख उदाहरण है। इसमें प्रशिक्षुओं को वास्तविक प्रशासनिक समस्याओं के लिखित विवरण प्रदान किए जाते हैं, जिन पर वे गहन विचार-विमर्श और सूक्ष्म विश्लेषण करते हैं। यह विधि उन्हें दैनिक कार्य के दबाव से मुक्त होकर चिंतन करने और समस्या-समाधान का कौशल विकसित करने का अवसर प्रदान करती है। इसके विपरीत, मार्गदर्शन और कार्य परिवर्तन जैसी विधियां प्रत्यक्ष रूप से कार्य करते हुए सीखने से संबंधित होती हैं, जो कार्य-पर प्रशिक्षण कहलाती हैं।

230. (C) केवल 2 और 3
पदोन्नति किसी कर्मचारी के करियर में एक सकारात्मक और ऊर्ध्वमुखी गति है, जो उसके श्रेष्ठ प्रदर्शन और अनुभव को आधिकारिक मान्यता प्रदान करती है। इसमें न केवल वेतन में वृद्धि होती है, बल्कि कर्मचारी की प्रतिष्ठा और संगठनात्मक उत्तरदायित्वों में भी बढ़ोतरी होती है। पदोन्नति प्रणालियों के दो

Click Here to Buy book on Amazon

शिकायतों और उनके कदाचार की जांच हेतु संवैधानिक रूप से भिन्न प्रक्रियाएं और संस्थागत व्यवस्थाएं विद्यमान हैं। लोकपाल का मुख्य ध्यान कार्यकारी भ्रष्टाचार पर नियंत्रण स्थापित करना है। यह सुनिश्चित करता है कि शासन के विभिन्न अंगों के बीच शक्तियों का संतुलन बना रहे और न्यायपालिका का आंतरिक अनुशासन और गरिमा बनी रहे।

215. (D) समान स्तर की कठिनाई वाले अधिक कार्य जोड़ना।
कार्य विस्तार अभिप्रेरणा की एक तकनीक है जिसमें किसी कर्मचारी के कार्य के दायरे को विस्तृत किया जाता है। इसमें कर्मचारी को उसके वर्तमान पद और स्तर पर ही कुछ और विविध कार्य सौंपे जाते हैं। इसका उद्देश्य कार्य की एकरसता को दूर करना और कर्मचारी को संगठन के विभिन्न आयामों से जोड़ना है। यह 'कार्य समृद्धि' से भिन्न है, क्योंकि इसमें उत्तरदायित्व या अधिकार का स्तर नहीं बढ़ता, बल्कि केवल कार्यों की संख्या में वृद्धि होती है। यह कर्मचारी को अपनी कार्यक्षमता का अधिक उपयोग करने और विविध अनुभव प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है, जिससे कार्य में अरुचि उत्पन्न नहीं होती।

216. (A) राजनीतिक विचारधारा की परवाह किए बिना सरकार की सेवा करनी चाहिए।
नौकरशाही तटस्थता का सिद्धांत संसदीय लोकतंत्र का एक आधार स्तंभ है। इसका अर्थ है कि लोक सेवकों को अपनी व्यक्तिगत राजनीतिक पसंद या विचारधारा को अपने आधिकारिक कार्य से सर्वथा दूर रखना चाहिए। सरकार चाहे किसी भी राजनीतिक दल की हो, लोक सेवक का कर्तव्य है कि वह पूरी निष्ठा, व्यावसायिकता और ईमानदारी के साथ उसकी नीतियों को क्रियान्वित करे। लोक सेवक को केवल संविधान और कानून के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए। यह तटस्थता प्रशासन में स्थिरता सुनिश्चित करती है और यह विश्वास दिलाती है कि शासन व्यवस्था किसी दल विशेष की नहीं, बल्कि संपूर्ण जनता की सेवा हेतु समर्पित है।

217. (C) प्रेषक को यह जाँचने की अनुमति देता है कि क्या संदेश समझा गया है।
संचार चक्र तब तक अपूर्ण माना जाता है जब तक कि प्राप्तकर्ता से प्रतिपुष्टि प्राप्त न हो जाए। प्रतिपुष्टि वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से प्रेषक को यह ज्ञात होता है कि उसका संदेश प्राप्तकर्ता तक पहुँच गया है और उसे उसी अर्थ में समझा गया है जैसा वह चाहता था। यह दो-तरफा संचार सुनिश्चित करता है और भ्रांतियों को दूर करने का अवसर प्रदान करता है। प्रभावी प्रतिपुष्टि से कार्य के निष्पादन में सुधार होता है और प्रेषक को अपनी संचार शैली को और अधिक उत्कृष्ट बनाने में सहायता प्राप्त होती है। इसके बिना संचार केवल सूचना का एकतरफा और निष्प्राण प्रसारण बनकर रह जाता है।

218. (A) यह सुनिश्चित करना कि कर्मचारी नवीन कौशल न सीखें।
एक प्रभावी प्रशिक्षण कार्यक्रम का मूल उद्देश्य ही कर्मचारियों को नवीन कौशल, आधुनिक तकनीक और नए दृष्टिकोण से सुसज्जित करना है ताकि वे बदलते परिवेश में प्रासंगिक बने रहें। प्रशिक्षण से न केवल कर्मचारी की व्यक्तिगत दक्षता में वृद्धि होती है, बल्कि वह संगठन हेतु एक बहुमूल्य परिसंपत्ति बन जाता है। इससे उत्पादकता में सुधार होता है, मनोबल ऊँचा होता है और भविष्य में उच्च पदों के उत्तरदायित्व संभालने हेतु आत्मविश्वास जागृत होता है। इसके विपरीत, नवीन कौशल सीखने से रोकना किसी भी प्रशिक्षण का उद्देश्य नहीं हो सकता क्योंकि यह कर्मचारी और संगठन दोनों के विकास को अवरुद्ध करेगा।

219. (D) अक्षमता, भ्रष्टाचार और अस्थिरता।
लूट पद्धति की मुख्य आलोचना इसकी अनैतिकता और प्रशासनिक गिरावट के कारण की जाती है। जब नियुक्तियां केवल राजनीतिक वफादारी के आधार पर होती हैं, तो अक्सर अयोग्य व्यक्ति महत्वपूर्ण पदों पर आसीन हो जाते हैं, जिससे कार्य की गुणवत्ता निरंतर गिरती है। प्रत्येक चुनाव के पश्चात संपूर्ण प्रशासनिक ढांचे का परिवर्तन संगठन में निरंतरता को समाप्त कर देता है और भारी अनिश्चितता उत्पन्न करता है। यह प्रणाली भ्रष्टाचार को संस्थागत बना देती है क्योंकि अधिकारी जनहित के स्थान पर अपने राजनीतिक स्वामियों को प्रसन्न करने में संलग्न रहते हैं। इससे प्रशासन की साख जनता की दृष्टि में न्यून हो जाती है।

220. (B) P-3, Q-2, R-4, S-1
लोकपाल संघ स्तर पर उच्च पदाधिकारियों के भ्रष्टाचार की जांच करने वाला सर्वोच्च निकाय है। लोकायुक्त इसी भूमिका को राज्य स्तर पर निर्वहन करता है और राज्यों में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य सरकारी विभागों के भीतर सतर्कता गतिविधियों का पर्यवेक्षण करना और प्रशासनिक शुचिता सुनिश्चित करना है। प्रशासनिक अधिकरण विशेष रूप से सरकारी कर्मचारियों के सेवा संबंधी विवादों, जैसे पदोन्नति, वेतन और स्थानांतरण के प्रकरणों का त्वरित समाधान करने हेतु स्थापित किए गए हैं। ये संस्थाएं मिलकर प्रशासन में जवाबदेही, न्याय और भ्रष्टाचार मुक्ति का एक एकीकृत ढांचा निर्मित करती हैं।

221. (C) योग्यता को वस्तुनिष्ठ रूप से मापने में कठिनाई।
योग्यता सिद्धांत का उद्देश्य सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा को पदोन्नत करना है, किंतु सबसे बड़ी चुनौती यह है कि 'योग्यता' को निष्पक्ष और सटीक रूप से कैसे मापा जाए। अक्सर वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट या साक्षात्कार वरिष्ठों के व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों से प्रभावित हो सकते हैं, जिससे योग्य कर्मचारी पीछे छूट सकते हैं। योग्यता के मानदंड भिन्न-भिन्न पदों हेतु अलग होते हैं और उन्हें पूरी तरह से गणितीय या वस्तुनिष्ठ बनाना दुष्कर होता है। यदि मूल्यांकन की प्रक्रिया पारदर्शी और वैज्ञानिक न हो, तो यह कर्मचारियों में असंतोष और अन्याय की भावना उत्पन्न कर सकती है, जिससे पदोन्नति प्रणाली की संपूर्ण विश्वसनीयता कम हो जाती है।

222. (D) विधिक-तार्किक सत्ता पर आधारित एक सामाजिक संगठन।
मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही केवल सरकारी अधिकारियों का समूह नहीं है, बल्कि यह बड़े पैमाने के संगठनों के प्रबंधन का एक अत्यंत विकसित और तार्किक स्वरूप है। इसकी वैधता उन लिखित नियमों और कानूनों से प्राप्त होती है जो निर्वैयक्तिक होते हैं। यहाँ सत्ता का आधार किसी व्यक्ति की इच्छा नहीं,

Downloaded from www.pdf.tube

कर देता है। इसके विपरीत, 'हटाने' की प्रक्रिया में सेवा तो समाप्त हो जाती है, किंतु वह व्यक्ति भविष्य में किसी अन्य सरकारी सेवा हेतु आवेदन करने का पात्र बना रहता है। इस प्रकार, बर्खास्तगी एक कर्मचारी के व्यावसायिक भविष्य पर पूर्ण विराम लगा देती है, जबकि हटाना उसे एक दूसरा अवसर प्राप्त करने की किंचित संभावना छोड़ देता है, बशर्ते वह अन्य अहर्ताएं पूर्ण करता हो।

207. (A) स्थापित रीति-रिवाजों और प्राचीन परंपराओं पर।
मैक्स वेबर के अनुसार पारंपरिक सत्ता की वैधता इस विश्वास से प्राप्त होती है कि जो रीति-रिवाज शताब्दियों से चले आ रहे हैं, वे पवित्र और अटल हैं। इस व्यवस्था में शासक को शक्ति इसलिए प्राप्त होती है क्योंकि उसके परिवार या वंश ने ऐतिहासिक रूप से शासन किया है। अनुयायी नेता की आज्ञा का पालन व्यक्तिगत निष्ठा और परंपरा के प्रति सम्मान के कारण करते हैं, न कि लिखित विधिक नियमों के कारण। यह व्यवस्था प्रायः पितृसत्तात्मक होती है और इसमें योग्यता के स्थान पर विरासत को महत्व प्रदान किया जाता है। आधुनिक समाज में यह सत्ता धीरे-धीरे विधिक-तार्किक सत्ता द्वारा प्रतिस्थापित कर दी गई है।

208. (B) विभाग के प्रभारी मंत्री।
संसदीय लोकतंत्र के सिद्धांत के अनुसार, एक सरकारी विभाग के समस्त कार्यों, नीतियों और उनके परिणामों हेतु अंतिम उत्तरदायित्व उस विभाग के कैबिनेट मंत्री का होता है। यद्यपि दैनिक प्रशासन लोक सेवकों द्वारा संचालित किया जाता है, किंतु किसी भी विफलता या अनियमितता हेतु मंत्री को ही संसद में उत्तर देना पड़ता है। इसे 'व्यक्तिगत उत्तरदायित्व' का सिद्धांत कहा जाता है। मंत्री विभाग का राजनीतिक प्रमुख होता है और लोक सेवक उसके विशेषज्ञ सलाहकार। चूंकि शक्तियां मंत्री के नाम पर प्रयोग की जाती हैं, इसलिए उनके सही या गलत उपयोग की अंतिम जिम्मेदारी भी उन्हीं की होती है, जो जन-जवाबदेही सुनिश्चित करती है।

209. (B) नेता और अनुयायी के बीच पुरस्कार आधारित आदान-प्रदान पर।
लेन-देन संबंधी नेतृत्व शैली इस धारणा पर आधारित है कि कर्मचारी मुख्य रूप से पुरस्कार और दंड के माध्यम से अभिप्रेरित होते हैं। इस शैली में नेता स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करता है और श्रेष्ठ प्रदर्शन के बदले वेतन वृद्धि, बोनस या पदोन्नति जैसे पुरस्कारों का वचन देता है, जबकि लक्ष्यों को पूर्ण न करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रयोग किया जाता है। यह नेता और अनुयायी के बीच एक संविदात्मक संबंध की भांति है जहाँ ध्यान कार्यों के कुशल निष्पादन और यथास्थिति बनाए रखने पर होता है। यह शैली उन कार्यों हेतु प्रभावी है जहाँ स्पष्ट प्रक्रियाएं और मानक परिणाम नितांत आवश्यक होते हैं।

210. (A) पर्याप्त संसाधनों का संग्रहण।
विकास योजना की सफलता हेतु न केवल श्रेष्ठ विचारों की आवश्यकता होती है, बल्कि उन्हें धरातल पर क्रियान्वित करने हेतु पर्याप्त धन, सामग्री और प्रशिक्षित मानव संसाधन का होना भी अनिवार्य है। भारत जैसे देशों में प्रायः योजनाओं के लक्ष्य तो अत्यंत महत्वाकांक्षी रखे जाते हैं, किंतु उनके क्रियान्वयन हेतु आवश्यक वित्तीय और भौतिक संसाधनों का संग्रहण करना एक बहुत बड़ी चुनौती रही है। इसके परिणामस्वरूप अनेक परियोजनाएं समय पर पूर्ण नहीं हो पातीं। संसाधनों का कुशलतापूर्वक दोहन और उनका न्यायसंगत आवंटन ही विकास की गति को सतत और प्रभावी बनाने की कुंजी है, जो राष्ट्र निर्माण में सहायक होती है।

211. (C) उद्यमी और नागरिक-केंद्रित।
उदारीकरण ने प्रशासनिक संस्कृति में एक आधारभूत परिवर्तन की मांग की है। अब नौकरशाहों को केवल फाइलों तक सीमित रहने के स्थान पर 'प्रशासनिक उद्यमी' की भांति चिंतन करने की आवश्यकता है, जो संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करें और कम समय में श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करें। इसके साथ ही, शासन का केंद्र 'नागरिक' होना चाहिए, न कि केवल 'नियम'। इसका अर्थ है कि प्रशासन को जनता की समस्याओं के प्रति अधिक संवेदनशील, उत्तरदायी और पारदर्शी होना चाहिए। यह दृष्टिकोण नागरिकों को केवल प्राप्तकर्ता के रूप में नहीं, बल्कि सेवाओं के विधिक हकदार हितधारकों के रूप में देखता है, जो आधुनिक सुशासन की पहचान है।

212. (D) कराधान के लिए सरकार के प्रस्ताव।
वित्त विधेयक बजट प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है जो सरकार के राजस्व संग्रहण के विधिक पक्ष को दर्शाता है। इसमें नए कर अधिरोपित करने, विद्यमान करों की दरों में परिवर्तन करने या उन्हें निरंतर जारी रखने के प्रस्ताव सम्मिलित होते हैं। संविधान के अनुसार, संसद की अनुमति के बिना सरकार कोई भी कर नहीं लगा सकती। अतः बजट के व्यय पक्ष हेतु विनियोग विधेयक की आवश्यकता होती है, तो आय या राजस्व पक्ष हेतु वित्त विधेयक को पारित करना अनिवार्य होता है। यह विधेयक सरकार को आवश्यक वित्तीय संसाधन जुटाने का संवैधानिक अधिकार प्रदान करता है ताकि वह देश के शासन का सुचारु संचालन कर सके।

213. (A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।
भ्रष्टाचार सुशासन के समस्त स्तंभों, जैसे पारदर्शिता, जवाबदेही और समानता को खंडित कर देता है। जब निर्णय व्यक्तिगत लाभ हेतु लिए जाते हैं, तो सार्वजनिक हित की उपेक्षा होती है और विकास हेतु आवंटित संसाधन अनुपयुक्त हाथों में चले जाते हैं। इससे समाज में आर्थिक असमानता की खाई और गहरी हो जाती है क्योंकि सेवाओं का लाभ केवल वे ही प्राप्त कर पाते हैं जो रिश्वत देने में सक्षम हैं। भ्रष्टाचार संसाधनों के न्यायसंगत वितरण में बड़ी बाधा उत्पन्न करता है और लोकतंत्र की जड़ों को दुर्बल करता है। इसलिए, भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष सुशासन की स्थापना हेतु नितांत अनिवार्य और प्राथमिक शर्त है।

214. (B) न्यायपालिका।
लोकपाल का अधिकार क्षेत्र यद्यपि अत्यंत व्यापक है और इसमें प्रधानमंत्री, मंत्रियों तथा लोक सेवकों को सम्मिलित किया गया है, किंतु न्यायपालिका के सदस्यों को इससे पृथक रखा गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता को अक्षुण्ण बनाए रखने हेतु यह निर्णय लिया गया है। न्यायाधीशों के विरुद्ध

NODIA

मुख्य आधार स्तंभ वरिष्ठता और योग्यता हैं। वरिष्ठता निष्पक्षता और अनुभव को महत्व प्रदान करती है, जबकि योग्यता श्रेष्ठ प्रदर्शन और नवीन प्रतिभा को पुरस्कृत करती है। इन दोनों के बीच उचित संतुलन बनाना एक कुशल कार्मिक नीति की पहचान है। पदोन्नति को अधोमुखी गति कहना तकनीकी रूप से त्रुटिपूर्ण है।

231. (D) एक समूह को लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रभावित और अभिप्रेरित करना।
संगठन में नेतृत्व की भूमिका केवल सत्ता संचालित करने या आदेश देने तक सीमित नहीं है। एक वास्तविक नेता वह है जो अपने अनुयायियों के भीतर एक साझा विजन जागृत करता है और उन्हें स्वेच्छा से संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु प्रेरित करता है। वह टीम के सदस्यों का मार्गदर्शन करता है, उनमें अटूट आत्मविश्वास भरता है और कठिन परिस्थितियों में उनका संबल बनता है। नेतृत्व का मुख्य कार्य लोगों की ऊर्जा को सटीक दिशा में मोड़ना और एक ऐसी कार्य संस्कृति विकसित करना है जहाँ प्रत्येक व्यक्ति अपनी पूर्ण क्षमता का उपयोग कर सके। प्रभावी नेतृत्व ही किसी संगठन को सफल और गतिशील बनाता है।

232. (A) अक्षमता और लालफीताशाही
यद्यपि नौकरशाही का शास्त्रीय अर्थ एक व्यवस्थित प्रशासनिक ढांचा है, किंतु सामान्य बोलचाल में इसका प्रयोग अक्सर नकारात्मक संदर्भ में किया जाता है। यह उन स्थितियों को परिलक्षित करता है जहाँ नियमों की कठोरता, फाइलों का अनावश्यक विलंब और निर्णय लेने में अत्यधिक औपचारिकता के कारण कार्य अवरुद्ध हो जाता है। जब नौकरशाह जनता के प्रति असंवेदनशील हो जाते हैं और केवल प्रक्रिया को ही परिणाम से श्रेष्ठ मानते हैं, तो इसे 'नौकरशाही की बुराई' कहा जाता है। यह छवि आधुनिक शासन हेतु एक बड़ी चुनौती है, जिसे पारदर्शिता और नागरिक-केंद्रित सुधारों के माध्यम से दूर करने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है।

233. (C) इसकी प्रक्रियात्मक कठोरता और अभिजात दृष्टिकोण।
विकास की बदलती मांगों के प्रति नौकरशाही के अनुकूल न हो पाने का एक प्रमुख कारण उसकी परंपरागत मानसिकता और नियमों का अंधानुकरण है। नौकरशाह अक्सर स्वयं को जनता से पृथक एक विशिष्ट 'अभिजात वर्ग' के रूप में देखते हैं, जिससे सामान्य जन की समस्याओं के प्रति उनमें सहानुभूति का अभाव हो जाता है। इसके अतिरिक्त, नियमों के प्रति उनकी अत्यधिक निष्ठा उन्हें नवाचार करने और जोखिम लेने से अवरुद्ध करती है। विकास हेतु जिस गति और संवेदनशीलता की नितांत आवश्यकता होती है, वह अक्सर नौकरशाही की इस पुरानी और अनम्य संरचनात्मक जकड़न के कारण पूर्णतः प्राप्त नहीं हो पाती है।

234. (A) पीटर ए. पीर
शून्य-आधारित बजटिंग की अवधारणा को सर्वप्रथम पीटर ए. पीर ने 1970 के दशक में एक निजी उपक्रम में सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया था। इसके पश्चात, इसे अमेरिकी प्रशासन में जॉर्जिया के राज्यपाल के रूप में जिमी कार्टर द्वारा अपनाया गया और बाद में राष्ट्रपति बनने पर उन्होंने इसे संपूर्ण संघीय बजट में अनिवार्य कर दिया। यह तकनीक इस क्रांतिकारी विचार पर आधारित थी कि बजट की प्रत्येक मद को प्रत्येक वर्ष नए सिरे से न्यायोचित सिद्ध किया जाना चाहिए। इसने पारंपरिक वृद्धिशील बजटिंग की न्यूनताओं को दूर करने और संसाधनों के अधिक तार्किक आवंटन की दिशा में एक नवीन मार्ग प्रशस्त किया।

235. (D) निर्णय लेने और कार्यान्वयन की प्रक्रिया पर।
सुशासन का मुख्य बल केवल इस बात पर नहीं है कि सरकार क्या कार्य करती है, बल्कि इस पर है कि वह उन्हें कैसे संपन्न करती है। यह उन प्रक्रियाओं की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करता है जिनके माध्यम से निर्णय लिए जाते हैं और उन्हें क्रियान्वित किया जाता है। सुशासन यह सुनिश्चित करता है कि निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी हो, जनता की उसमें सक्रिय भागीदारी हो और वह विधिक दायरे में हो। यह शासन की प्रभावशीलता और संवेदनशीलता का निष्पक्ष मूल्यांकन करता है। जब प्रक्रियाएं सही और जवाबदेह होती हैं, तो उनका परिणाम भी स्वाभाविक रूप से जनकल्याणकारी और न्यायसंगत होता है, जो सुशासन का मूल लक्ष्य है।

236. (B) लोकपाल
द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी रिपोर्ट "शासन में नैतिकता" में भ्रष्टाचार को समूल नष्ट करने हेतु अनेक महत्वपूर्ण सुझाव प्रदान किए थे। आयोग ने दृढ़ता से सिफारिश की थी कि राष्ट्रीय स्तर पर एक स्वतंत्र और शक्तिशाली लोकपाल की स्थापना की जानी चाहिए, जो बिना किसी राजनीतिक प्रभाव के उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों के विरुद्ध जांच करने में सक्षम हो। आयोग का पूर्ण विश्वास था कि केवल एक सुदृढ़ विधिक और संस्थागत ढांचा ही सार्वजनिक जीवन में गिरते नैतिक मानकों को पुनः स्थापित कर सकता है और नागरिकों का शासन में विश्वास जागृत कर सकता है, जो लोकतंत्र हेतु अनिवार्य है।

237. (C) उच्च विवेकाधिकार और कम जवाबदेही के साथ सत्ता का एकाधिकार।
भ्रष्टाचार के लिए रॉबर्ट क्लिटगार्ड का प्रसिद्ध सूत्र यह स्पष्ट करता है कि जब किसी अधिकारी के पास शक्तियों का एकाधिकार होता है और उसके पास निर्णय लेने के व्यापक विवेकाधिकार होते हैं, तथा इन सबके साथ यदि जवाबदेही का अभाव हो, तो भ्रष्टाचार की संभावना अत्यधिक प्रबल हो जाती है। विवेकाधिकारों का स्पष्ट नियमों के अभाव में प्रयोग अक्सर पक्षपात और रिश्वतखोरी को जन्म देता है। अतः भ्रष्टाचार को न्यून करने हेतु शक्तियों का विकेंद्रीकरण करना, प्रक्रियाओं को पूर्णतः पारदर्शी बनाना और अधिकारियों को उनके प्रत्येक निर्णय हेतु विधिक रूप से जवाबदेह बनाना नितांत अनिवार्य और प्राथमिक कार्य है।

238. (C) कथन I असत्य है लेकिन कथन II सत्य है।
यद्यपि उच्च मनोबल और उत्पादकता के बीच सकारात्मक संबंध होता है, किंतु यह कहना त्रुटिपूर्ण होगा कि उच्च मनोबल सदैव उच्च उत्पादकता की पूर्ण गारंटी देता है। मनोबल

Click Here to Buy book on Amazon

के मंत्रियों, विधायकों और लोक सेवकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की स्वतंत्र जांच करना है। इसकी स्थापना राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित कानूनों के माध्यम से की जाती है। चूँकि राज्य सरकार के कार्य सीधे आम जनता के दैनिक जीवन को प्रभावित करते हैं, इसलिए लोकायुक्त की भूमिका स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक शुचिता और नागरिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण है।

255. (A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
पदोन्नति हेतु वरिष्ठता का सिद्धांत प्रबंधकीय दृष्टि से अत्यंत सरल और विवाद मुक्त है क्योंकि यह केवल सेवा की अवधि पर आधारित होता है। सेवा के वर्षों की गणना करना एक पूर्णतः वस्तुनिष्ठ कार्य है जिसमें पक्षपात, व्यक्तिगत पसंद या भेदभाव की कोई संभावना नहीं रहती। कर्मचारी को ज्ञात होता है कि एक निश्चित समय के पश्चात उसकी पदोन्नति निश्चित है, जिससे उसमें सुरक्षा की भावना जागृत होती है। चूँकि इसमें किसी के प्रदर्शन का व्यक्तिपरक मूल्यांकन नहीं करना पड़ता, इसलिए यह प्रशासनिक रूप से लागू करने में सर्वाधिक सुगम और स्पष्ट मानदंड माना जाता है, जो संगठन में अनावश्यक टकराव को रोकता है।

256. (B) वर्तमान कर्मचारियों के मनोबल को प्रभावित कर सकती है।
यद्यपि सीधी भर्ती संगठन में नवीन प्रतिभा और विशेषज्ञता लाती है, किंतु उच्च स्तरों पर इसे लागू करने से संगठन के भीतर पूर्व से कार्यरत अनुभवी कर्मचारियों के मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। जब निचले स्तर के कर्मचारी देखते हैं कि वरिष्ठ पदों को बाहरी व्यक्तियों से भरा जा रहा है, तो उन्हें अपनी पदोन्नति के अवसर धूमिल होते दिखाई देते हैं। इससे उनमें हताशा, असुरक्षा और संगठन के प्रति अरुचि उत्पन्न हो सकती है। वे अपनी वर्षों की सेवा और अनुभव की उपेक्षा अनुभव कर सकते हैं। इसलिए, एक कुशल कार्मिक नीति को सीधी भर्ती और आंतरिक पदोन्नति के बीच सूक्ष्म संतुलन बनाना पड़ता है।

257. (B) निष्पादन मूल्यांकन (परफॉर्मेंस अप्रेजल)
'हेलो प्रभाव' निष्पादन मूल्यांकन के दौरान होने वाली एक मनोवैज्ञानिक त्रुटि है। इसमें मूल्यांकनकर्ता किसी कर्मचारी की एक विशिष्ट सकारात्मक विशेषता या उपलब्धि से इतना प्रभावित हो जाता है कि वह उसके अन्य समस्त पहलुओं और न्यूनताओं का भी अनुकूल मूल्यांकन कर देता है। इसके विपरीत, 'हॉर्न प्रभाव' में एक नकारात्मक विशेषता के कारण संपूर्ण प्रदर्शन को त्रुटिपूर्ण मान लिया जाता है। यह प्रभाव मूल्यांकन की वस्तुनिष्ठता को नष्ट कर देता है क्योंकि यह तथ्यों के स्थान पर एक समग्र धारणा पर आधारित होता है। इससे योग्य कर्मचारियों के साथ अन्याय हो सकता है और संगठन को अपने कार्यबल की वास्तविक क्षमताओं का सही ज्ञान नहीं मिल पाता।

258. (A) मशीन के पुर्जे, जो आर्थिक प्रोत्साहनों से अभिप्रेरित होते हैं।
शास्त्रीय संगठन सिद्धांत कर्मचारियों को संगठन रूपी मशीन के निर्जीव पुर्जों के समान मानते थे। इन सिद्धांतों का मुख्य बल संरचना, नियमों और कार्य के विशेषीकरण पर था। उनका मानना था कि मनुष्य स्वभाव से आलसी होता है और वह केवल आर्थिक लाभ या उच्च वेतन हेतु ही कार्य करता है। यहाँ मानवीय भावनाओं, सामाजिक संबंधों या मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ण उपेक्षा की गई। कर्मचारियों को केवल उत्पादकता बढ़ाने के साधन के रूप में देखा गया, जिन्हें कठोर नियंत्रण और मौद्रिक पुरस्कारों के माध्यम से प्रबंधित किया जाना चाहिए। यह दृष्टिकोण अत्यधिक यांत्रिक और अमानवीय माना गया, जिसकी बाद में आलोचना हुई।

259. (C) मंत्री के समक्ष तथ्यों और विकल्पों को प्रस्तुत करना।
संसदीय लोकतंत्र में लोक सेवक की भूमिका एक निष्पक्ष और विशेषज्ञ सलाहकार की होती है। नीति निर्माण के दौरान, लोक सेवक का कर्तव्य है कि वह समस्या से संबंधित समस्त प्रासंगिक आंकड़े, पूर्व अनुभव और विभिन्न विकल्पों के संभावित परिणामों को मंत्री के सम्मुख स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करे। उसे बिना किसी राजनीतिक दबाव के निडर होकर उन जोखिमों की ओर भी संकेत करना चाहिए जो किसी विशिष्ट नीति से उत्पन्न हो सकते हैं। यद्यपि अंतिम निर्णय लेने का अधिकार और जिम्मेदारी मंत्री की होती है, किंतु लोक सेवक द्वारा प्रदान की गई गुणवत्तापूर्ण और तथ्य-आधारित सलाह ही एक प्रभावी नीति की आधारशिला रखती है।

NODIA

260. (B) केवल 2 और 3
सुशासन केवल प्रशासनिक दक्षता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक अवधारणा है जो मानवीय गरिमा और लोक कल्याण को केंद्र में रखती है। इसमें कानून का शासन, पारदर्शिता, जवाबदेही और निर्णय प्रक्रिया में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी जैसे आवश्यक तत्व सम्मिलित हैं। सुशासन का मुख्य लक्ष्य भ्रष्टाचार को न्यूनतम करना, संसाधनों का न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करना और प्रशासन को जनता की आवश्यकताओं के प्रति अधिक संवेदनशील बनाना है। यह एक ऐसी शासन व्यवस्था है जो समाज के अत्यंत दुर्बल वर्ग की वाणी को सुनती है और समावेशी विकास को प्रोत्साहित करती है। दक्षता इसका एक परिणाम है, उद्देश्य नहीं।

261. (C) नागरिकों को 'ग्राहकों' के रूप में मानना।
नवीन सार्वजनिक प्रबंधन सार्वजनिक क्षेत्र में निजी क्षेत्र की कुशल प्रबंधन शैलियों को अपनाने का समर्थन करता है। इसका एक प्रमुख विचार यह है कि सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को नागरिक केवल एक उपकार न मानें, बल्कि वे स्वयं को 'ग्राहकों' के रूप में देखें जिन्हें गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध सेवा प्राप्त करने का विधिक अधिकार है। यह दृष्टिकोण प्रशासन में प्रतिस्पर्धा, लागत-प्रभावशीलता और परिणाम-उन्मुखता को बढ़ावा देता है। जब नागरिकों को ग्राहक माना जाता है, तो प्रशासन उनकी संतुष्टि और प्रतिपुष्टि के प्रति अधिक गंभीर हो जाता है, जिससे सार्वजनिक सेवाओं के स्तर में व्यापक सुधार संभव होता है।

262. (B) राष्ट्रपति को, संसद के समक्ष रखे जाने हेतु।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151 के अनुसार, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघ के खातों से संबंधित अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपते हैं। राष्ट्रपति का यह संवैधानिक

उद्देश्य कर्मचारी को विविध अनुभव प्रदान करना, संगठन की बदलती आवश्यकताओं को पूर्ण करना या कार्यस्थल पर नवीनता लाना होता है। यह पदोन्नति से सर्वथा भिन्न है क्योंकि इसमें पदानुक्रम में ऊपर की ओर कोई गति नहीं होती। क्षैतिज गतिशीलता से कर्मचारी के कौशल में बहुमुखी प्रतिभा आती है और वह संगठन के विभिन्न पहलुओं को गहराई से समझ पाता है।

247. (D) लोगों को तब तक पदोन्नत किया जाता है जब तक वे अपनी अक्षमता के स्तर तक नहीं पहुँच जाते।
पीटर सिद्धांत संगठनों में पदोन्नति की एक विडंबना को परिलक्षित करता है। यह सुझाव देता है कि यदि कोई व्यक्ति अपने वर्तमान पद पर श्रेष्ठ कार्य करता है, तो उसे उच्च पद पर पदोन्नत कर दिया जाता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक वह एक ऐसे पद पर नहीं पहुँच जाता जहाँ वह कार्य करने में सक्षम नहीं होता (अक्षमता का स्तर)। इसके पश्चात उसकी पदोन्नति अवरुद्ध हो जाती है, किंतु वह उसी पद पर बना रहता है। परिणामस्वरूप, संगठन के अनेक महत्वपूर्ण पद ऐसे व्यक्तियों से भर जाते हैं जो उस विशिष्ट कार्य हेतु अयोग्य होते हैं, जिससे संगठन की समग्र कार्यक्षमता और उत्पादकता प्रभावित होती है।

248. (A) पूर्ण सूचना रखता है और सभी विकल्पों का मूल्यांकन करता है।
निर्णय लेने का शास्त्रीय तार्किक प्रारूप 'आर्थिक मानव' की धारणा पर आधारित है। यह मानता है कि निर्णय लेने वाला व्यक्ति पूर्णतः तर्कसंगत होता है और उसके पास समस्या से संबंधित समस्त आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध होती हैं। वह संभावित सभी विकल्पों की एक सूची तैयार करता है और प्रत्येक विकल्प के परिणामों का सूक्ष्म विश्लेषण करता है। अंत में, वह उस विकल्प का चयन करता है जो संगठनात्मक लाभ को अधिकतम करता हो। यद्यपि, वास्तविकता में समय और सूचना की सीमाओं के कारण इस पूर्ण तार्किकता को प्राप्त करना दुष्कर होता है, फिर भी यह मॉडल आदर्श निर्णय प्रक्रिया हेतु एक मानक प्रदान करता है।

249. (C) तदर्थ और मनमाने नियमों की प्रणाली
मैक्स वेबर की आदर्श नौकरशाही का मुख्य आधार ही यह है कि वह व्यक्तिगत इच्छा पर नहीं, बल्कि स्थिर, स्पष्ट और निर्वैयक्तिक नियमों की एक व्यवस्था पर संचालित होती है। तदर्थ या मनमाने नियम प्रशासन में अनिश्चितता और पक्षपात उत्पन्न करते हैं, जो वेबर के तार्किक मॉडल के पूर्णतः विपरीत हैं। वेबर के अनुसार, नियमों को लिखित रूप में होना चाहिए और वे सभी के लिए समान रूप से लागू होने चाहिए। नियमों की यह स्थिरता ही संगठन को एक स्थायी ढांचा प्रदान करती है और प्रशासनिक कार्यों में पूर्वानुमान और निष्पक्षता सुनिश्चित करती है, जो आधुनिक शासन की कुशलता और विश्वसनीयता हेतु अनिवार्य है।

250. (D) P-4, Q-2, R-1, S-3
विशेषक सिद्धांत मानता है कि नेतृत्व के गुण जन्मजात होते हैं और यह नेता के व्यक्तित्व पर ध्यान केंद्रित करता है। व्यवहारवादी सिद्धांत नेता द्वारा की जाने वाली गतिविधियों, जैसे कार्य-उन्मुख व्यवहार का अध्ययन करता है। स्थितिजन्य सिद्धांत यह स्पष्ट करता है कि नेतृत्व की प्रभावशीलता परिस्थितियों और अनुयायियों की क्षमता पर निर्भर करती है। परिवर्तनकारी सिद्धांत वह है जहाँ नेता अपने अनुयायियों को प्रेरित करता है और उन्हें सामान्य स्वार्थ से ऊपर उठाकर संगठन के उच्च लक्ष्यों के प्रति समर्पित करता है। ये सिद्धांत नेतृत्व की जटिलता को समझने के विभिन्न आयाम प्रस्तुत करते हैं, जो सफलता हेतु महत्वपूर्ण हैं।

251. (D) सहयोग और समाधान के लिए एक मंच प्रदान करना।
ह्विटली परिषदों और संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र जैसी संस्थाओं का मूल दर्शन औद्योगिक लोकतंत्र और शांति है। इनका उद्देश्य कर्मचारी और प्रबंधन के बीच की दूरी को न्यून करना है ताकि वे एक साथ बैठकर साझा समस्याओं पर चर्चा कर सकें। यह तंत्र केवल व्यथाओं को सुनने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह प्रशासन में कर्मचारियों की भागीदारी सुनिश्चित करता है और सेवा शर्तों के सुधार हेतु सुझाव आमंत्रित करता है। जब विवादों का समाधान आपसी सहमति से होता है, तो संगठन में हड़ताल और संघर्ष की संभावना कम हो जाती है, जिससे कार्य वातावरण सुखद, अनुशासित और उत्पादक बना रहता है।

252. (B) चमड़े का थैला या बटुआ
'बजट' शब्द की व्युत्पत्ति पुराने फ्रांसीसी शब्द 'बोउगेट' से हुई है, जिसका अर्थ एक छोटा चमड़े का थैला होता है। ऐतिहासिक रूप से, ब्रिटेन के वित्त मंत्री जब संसद में वित्तीय प्रस्ताव प्रस्तुत करने आते थे, तो वे अपने प्रलेखों को एक चमड़े के थैले में रखते थे। जब वे उस थैले को खोलते थे, तो उसे 'बजट खोलना' कहा जाने लगा। समय के साथ, यह शब्द उस थैले के भीतर रखे वित्तीय विवरण और आगामी वर्ष के आय-व्यय के अनुमानों का पर्याय बन गया। आज यह शब्द संपूर्ण विश्व में सरकार और संगठनों की वार्षिक वित्तीय योजना हेतु उपयोग किया जाता है, जो उनकी प्राथमिकताओं का दर्पण है।

253. (B) पारदर्शिता जवाबदेही के लिए एक अनिवार्य शर्त है।
लोक प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। पारदर्शिता का अर्थ है सूचनाओं और प्रक्रियाओं का खुलापन। जब तक नागरिकों और निगरानी संस्थाओं के पास यह सूचना नहीं होगी कि निर्णय कैसे और क्यों लिए गए, तब तक वे संबंधित अधिकारियों को उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते। सूचना का अभाव जवाबदेही को असंभव बना देता है। इसलिए, पारदर्शिता वह आधारशिला है जिस पर जवाबदेही की संरचना निर्मित होती है। सूचना का अधिकार जैसे कानून पारदर्शिता बढ़ाकर अंततः लोक सेवकों की जवाबदेही को ही सुदृढ़ करते हैं, जिससे भ्रष्टाचार मुक्त और उत्तरदायी शासन व्यवस्था का निर्माण संभव होता है।

254. (D) राज्य स्तर
लोकायुक्त की संस्था भारत में राज्य स्तर पर भ्रष्टाचार और कुप्रशासन के विरुद्ध जांच करने वाला एक प्रमुख शिकायत निवारण तंत्र है। यह स्कैंडिनेवियाई देशों के 'ओम्बुड्समैन' मॉडल पर आधारित है। लोकायुक्त का मुख्य कार्य राज्य

Downloaded from www.pdf.tube

270. (D) मनमानी शक्ति की अनुपस्थिति।
विधि का शासन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आयाम यह है कि प्रशासन की शक्तियां असीमित या स्वैच्छिक नहीं हो सकतीं। प्रत्येक सरकारी कार्य और निर्णय का आधार कोई न कोई विधिक नियम होना चाहिए। यह सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी अधिकारी अपनी व्यक्तिगत पसंद, द्वेष या मनमर्जी से नागरिकों के अधिकारों का हनन न कर सके। जहाँ मनमानी शक्ति विद्यमान होती है, वहाँ तानाशाही और अन्याय का प्रादुर्भाव होता है। विधि का शासन समस्त नागरिकों को यह सुरक्षा प्रदान करता है कि उनके साथ निष्पक्ष और कानून सम्मत व्यवहार किया जाएगा, जो एक न्यायपूर्ण समाज की बुनियादी और अनिवार्य पहचान है।

271. (A) प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन।
विभागीय जांच एक ऐसी अर्ध-न्यायिक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य किसी कर्मचारी पर अधिरोपित आरोपों की निष्पक्षता से छानबीन करना है। इसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष 'प्राकृतिक न्याय' के सिद्धांतों का अनुपालन करना है, जिसमें यह अनिवार्य है कि किसी को भी बिना सुने दंडित नहीं किया जाना चाहिए। जांच के दौरान कर्मचारी को अपने बचाव में साक्ष्य प्रस्तुत करने, गवाहों से जिरह करने और अपना पक्ष रखने का पूर्ण अवसर प्रदान किया जाता है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि कर्मचारी के विरुद्ध की जाने वाली कार्रवाई केवल द्वेष पर आधारित न होकर, ठोस तथ्यों और न्यायपूर्ण पद्धति पर आधारित हो, जिससे शुचिता बनी रहे।

272. (B) तार्किकता की सीमाओं के कारण 'संतोषजनक' विकल्प चुनते हैं।
हर्बर्ट साइमन ने शास्त्रीय 'पूर्ण तार्किकता' के विचार को चुनौती देते हुए 'सीमित तार्किकता' की अवधारणा प्रस्तुत की। उन्होंने तर्क दिया कि मानवीय मस्तिष्क की क्षमताएं, उपलब्ध सीमित समय और अपूर्ण सूचनाएं किसी भी प्रशासक को पूर्णतः तार्किक होने से रोकती हैं। इसलिए, एक निर्णय लेने वाला व्यक्ति समस्त संभावित विकल्पों का मूल्यांकन करने के स्थान पर केवल उन कतिपय विकल्पों पर विचार करता है जो उसे दृष्टिगोचर होते हैं। वह 'सर्वश्रेष्ठ' विकल्प खोजने के बजाय उस प्रथम विकल्प का चयन कर लेता है जो उसकी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूर्ण करता हो, जिसे साइमन ने संतोषजनक निर्णय की प्रक्रिया कहा है।

273. (B) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखापरीक्षा रिपोर्ट।
लोक लेखा समिति भारतीय संसद की एक अत्यंत महत्वपूर्ण वित्तीय समिति है जिसका मुख्य कार्य नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत वार्षिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों की सूक्ष्म जाँच करना है। समिति यह देखती है कि क्या सरकार ने धन उन्हीं उद्देश्यों पर व्यय किया है जिनके लिए संसद ने अनुमति प्रदान की थी और क्या कहीं कोई वित्तीय अनियमितता या अपव्यय हुआ है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इस प्रक्रिया में समिति के 'मित्र और मार्गदर्शक' के रूप में सहायता करते हैं। यह विधायी नियंत्रण का एक अत्यंत प्रभावी माध्यम है जो कार्यपालिका को वित्तीय प्रकरणों में जनता के प्रति पूर्णतः जवाबदेह बनाता है।

274. (A) निवारण प्राप्त करने हेतु विविध संस्थाओं का होना।
संस्थागत बहुलवाद का अर्थ है कि किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिकों की शिकायतों को सुनने और उन्हें न्याय प्रदान करने हेतु केवल एक ही नहीं, बल्कि अनेक भिन्न-भिन्न संस्थाएं विद्यमान होनी चाहिए। उदाहरण हेतु, भारत में लोकपाल, लोकायुक्त, सतर्कता आयोग, मानवाधिकार आयोग, सूचना आयोग और न्यायालय जैसे विविध मंच उपलब्ध हैं। यह बहुलता सुनिश्चित करती है कि यदि एक संस्था किसी कारणवश प्रभावी नहीं हो पाती, तो नागरिक के पास अन्य विकल्प सदैव खुले रहें। यह व्यवस्था प्रशासन पर विभिन्न दिशाओं से नियंत्रण बनाए रखती है और नागरिकों को अपनी समस्याओं के समाधान हेतु व्यापक और सुलभ अवसर प्रदान करती है।

275. (A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
1991 के आर्थिक सुधारों के पश्चात से लोक प्रशासन का परिदृश्य पूर्णतः परिवर्तित हो गया है। उदारीकरण ने राज्य की भूमिका को आर्थिक गतिविधियों के प्रत्यक्ष नियंत्रण और संचालन से विस्थापित कर एक 'सुगमकर्ता' के रूप में परिवर्तित कर दिया है। अब प्रशासन को निजी क्षेत्र के साथ सहयोग करना, बाजार की प्रतिस्पर्धा का नियमन करना और अधिक व्यावसायिकता का परिचय देना पड़ रहा है। यह नवीन भूमिका नौकरशाही हेतु चुनौतीपूर्ण है क्योंकि इसके लिए पुरातन नियंत्रणकारी मानसिकता को त्यागकर सेवा-उन्मुख, पारदर्शी और दक्ष दृष्टिकोण अपनाने की नितांत आवश्यकता है। यह परिवर्तन प्रशासनिक दक्षता और आर्थिक विकास में नवीन संतुलन है।

NODIA

276. (D) उच्च कर्मचारी टर्नओवर और बार-बार होने वाले संघर्ष।
संगठन में निम्न मनोबल का सर्वाधिक स्पष्ट और हानिकारक संकेत यह है कि कर्मचारी वहां कार्य करना पसंद नहीं करते और निरंतर सेवा त्याग देते हैं, जिसे 'उच्च कर्मचारी टर्नओवर' कहा जाता है। इसके अतिरिक्त, जब कर्मचारियों में व्यापक असंतोष होता है, तो प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच पारस्परिक विवाद और टकराव की घटनाएं निरंतर बढ़ जाती हैं। अनुशासनहीनता, कार्य में अरुचि और सहयोग का अभाव निम्न मनोबल के अन्य प्रमुख लक्षण हैं। ये स्थितियां संगठन की उत्पादकता को गंभीर रूप से न्यून करती हैं और यह दर्शाती हैं कि कार्य वातावरण में सुधार और कर्मचारियों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं पर ध्यान देना अनिवार्य है।

277. (C) संस्थागत और क्षेत्रीय प्रशिक्षण की वैकल्पिक अवधि।
प्रशिक्षण की सैंडविच पद्धति को 'सैद्धांतिक ज्ञान' और 'व्यावहारिक अनुभव' के बीच एक मजबूत सेतु माना जाता है। इसमें प्रशिक्षण को परतों में विभाजित किया जाता है; यथा, प्रशिक्षु सर्वप्रथम अकादमी में प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, पश्चात उन्हें वास्तविक कार्य स्थितियों को समझने हेतु जिला या क्षेत्रीय स्तर पर तैनात किया जाता है, और अंत में वे अपने अनुभवों को साझा करने और शेष ज्ञान अर्जन हेतु पुनः अकादमी लौटते हैं। यह निरंतर चक्र लोक सेवकों को कार्य की व्यावहारिक जटिलताओं के प्रति अधिक संवेदनशील बनाता

दायित्व है कि वे इस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखवाएं। इसके पश्चात, संसद की लोक लेखा समिति इस रिपोर्ट की विस्तृत जाँच करती है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि कार्यपालिका की वित्तीय गतिविधियों पर विधायी नियंत्रण सुदृढ़ बना रहे। इसी प्रकार, राज्यों के संबंध में यह रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपी जाती है, जिसे राज्य विधानमंडल के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है, जो वित्तीय जवाबदेही का चक्र पूर्ण करता है।

263. (D) सार्वजनिक निंदा और सामाजिक बहिष्कार।
भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने हेतु केवल विधिक और विभागीय दंड ही पर्याप्त नहीं हैं; 'सामाजिक दंड' भी एक अत्यंत प्रभावशाली भूमिका निर्वहन करता है। जब समाज भ्रष्ट अधिकारियों को सम्मान देने के स्थान पर उनकी सार्वजनिक निंदा करता है और उन्हें सामाजिक कार्यक्रमों या समूहों से बहिष्कृत कर देता है, तो यह व्यक्ति पर गहरा मनोवैज्ञानिक दबाव डालता है। सामाजिक प्रतिष्ठा की हानि अक्सर कारावास के भय से भी अधिक शक्तिशाली सिद्ध हो सकती है। भ्रष्टाचार के प्रति सामाजिक असहनशीलता का वातावरण लोक सेवकों को अनैतिक कार्यों से दूर रहने हेतु प्रेरित करता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा अक्षुण्ण रखना चाहता है।

264. (A) सरकार के कामकाज पर प्रश्न उठाने के लिए।
सूचना का अधिकार अधिनियम का मुख्य दर्शन नागरिकों को सक्रिय भागीदार के रूप में परिवर्तित करना है। यह कानून जनता को वह शक्ति प्रदान करता है जिससे वे सरकारी फाइलों, निविदाओं, योजनाओं और व्ययों का पूर्ण विवरण प्राप्त कर सकें। जब नागरिकों के पास सटीक सूचना होती है, तो वे सरकारी निर्णयों की तर्कसंगतता और उनके पीछे निहित उद्देश्यों पर प्रश्न उठा सकते हैं। यह प्रशासनिक मनमानी को अवरुद्ध करता है और लोक सेवकों को यह निरंतर स्मरण कराता है कि वे जनता के सेवक हैं। इस प्रकार, यह अधिनियम लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर सुदृढ़ करता है और शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही के नवीन मानक स्थापित करता है।

265. (A) 3, 2, 1, 4
कार्मिक प्रशासन का तार्किक जीवन चक्र भर्ती के साथ प्रारंभ होता है, जहाँ संगठन में नवीन कर्मियों का प्रवेश होता है। इसके तुरंत पश्चात, उन्हें उनके कार्य की आवश्यकताओं के अनुसार आवश्यक कौशल प्रदान करने हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है। जैसे-जैसे कर्मचारी अनुभव और विशेषज्ञता अर्जित करता है, उसे उसके श्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर उच्च पदों पर पदोन्नति प्रदान की जाती है। अंत में, सेवा की एक निश्चित अवधि पूर्ण करने के पश्चात, वह सेवानिवृत्ति के माध्यम से संगठन से विदा लेता है। यह व्यवस्थित क्रम सुनिश्चित करता है कि संगठन को निरंतर सक्षम जनशक्ति प्राप्त होती रहे और कर्मचारियों का करियर विकास भी नियमबद्ध हो।

266. (A) यथास्थितिवादी उन्मुखीकरण
विकास प्रशासन पारंपरिक प्रशासन के विपरीत एक गतिशील और भविष्योन्मुखी अवधारणा है। इसकी मुख्य विशेषताओं में सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन लाना, स्पष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करना और निर्णय प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना सम्मिलित है। यह प्रशासन को एक सक्रिय 'परिवर्तन अभिकर्ता' के रूप में देखता है। यथास्थिति बनाए रखना पारंपरिक प्रशासन का गुण हो सकता है, किंतु विकास प्रशासन हेतु यह एक बड़ी बाधा है क्योंकि विकास का अर्थ ही पुरातन और पिछड़ी व्यवस्थाओं को परिवर्तित कर नवीन और प्रगतिशील व्यवस्थाएं स्थापित करना है। अतः विकास प्रशासन सदैव परिवर्तन और नवाचार का समर्थन करता है, न कि यथास्थिति का।

267. (A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।
भारतीय नौकरशाही की प्रायः इसके 'अभिजात दृष्टिकोण' हेतु आलोचना की जाती है, जो ब्रिटिश औपनिवेशिक विरासत का परिणाम माना जाता है। अनेक बार नौकरशाह स्वयं को जनता के सेवक के स्थान पर एक शासक वर्ग के रूप में देखते हैं, जिससे सामान्य नागरिक और प्रशासन के बीच दूरी उत्पन्न हो जाती है। इसके विपरीत, विकास की चुनौतियों का सामना करने और जनकल्याणकारी योजनाओं को सफल बनाने हेतु ऐसी नौकरशाही की नितांत आवश्यकता है जो सहानुभूतिपूर्ण, विनम्र और जनता की समस्याओं के प्रति संवेदनशील हो। जब तक नौकरशाही का व्यवहार नागरिक-मैत्रीपूर्ण नहीं होगा, तब तक लोकतांत्रिक शासन के वास्तविक लक्ष्यों को प्राप्त करना दुष्कर होगा।

268. (B) राष्ट्रीय विकास और संवैधानिक सिद्धांत।
'प्रतिबद्ध नौकरशाही' की अवधारणा का प्रायः त्रुटिपूर्ण अर्थ निकाला जाता है, किंतु इसका वास्तविक और सकारात्मक अर्थ लोक सेवकों की संविधान के मूल्यों, सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय विकास के लक्ष्यों के प्रति अटूट निष्ठा है। यह किसी विशिष्ट राजनीतिक दल के प्रति वफादारी नहीं है, बल्कि देश के प्रगतिशील उद्देश्यों, जैसे गरीबी उन्मूलन और समानता, के प्रति एक सक्रिय और ऊर्जावान दृष्टिकोण है। एक प्रतिबद्ध नौकरशाह वह है जो केवल यंत्रवत कार्य नहीं करता, बल्कि वह नीतियों के पीछे निहित मानवीय और सामाजिक महत्व को समझता है और उन्हें सफल बनाने हेतु अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने का दृढ़ संकल्प लेता है।

269. (C) एक स्थायी रिकॉर्ड प्रदान करता है और सटीकता सुनिश्चित करता है।
प्रशासन में लिखित संचार को मौखिक संचार की तुलना में अधिक महत्व प्रदान किया जाता है क्योंकि यह भविष्य के संदर्भ हेतु एक ठोस और स्थायी साक्ष्य के रूप में कार्य करता है। लिखित प्रलेखों, जैसे फाइलों और परिपत्रों में सूचनाओं के विकृत होने की संभावना अत्यंत न्यून होती है, जो संदेश की सटीकता और स्पष्टता बनाए रखती है। यह आधिकारिक जवाबदेही निर्धारित करने में भी सहायक होता है क्योंकि यह स्पष्ट रहता है कि आदेश किसने प्रदान किया और कब दिया। इसके विपरीत, मौखिक संचार तीव्रता से तो प्रसारित होता है किंतु इसमें विस्मृति, त्रुटिपूर्ण अर्थ निकालने या साक्ष्य के अभाव की समस्या सदैव विद्यमान रहती है।

Click Here to Buy book on Amazon

केवल कार्य करने की मानसिक इच्छा और उत्साह है, जबकि उत्पादकता तकनीक, संसाधनों की उपलब्धता, प्रशिक्षण और कार्यप्रणाली जैसे अन्य भौतिक कारकों पर भी गहराई से निर्भर करती है। उदाहरण हेतु, एक अत्यंत उत्साहित कर्मचारी यदि प्राचीन उपकरणों या त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया से कार्य करता है, तो उसकी उत्पादकता न्यून रह सकती है। अतः मनोबल एक आवश्यक शर्त तो है, किंतु यह उत्पादकता को प्रभावित करने वाला एकमात्र कारक नहीं है।

239. (A) स्वयं कार्य के कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों का।
पद वर्गीकरण कार्मिक प्रशासन की एक वस्तुनिष्ठ प्रणाली है जो व्यक्ति के स्थान पर 'पद' पर केंद्रित होती है। इसमें यह मूल्यांकन किया जाता है कि किसी विशेष पद का निर्वहन करने हेतु कौन से कर्तव्य पूर्ण करने होंगे और उसकी जिम्मेदारी का स्तर क्या होगा। इसके आधार पर पदों को विभिन्न श्रेणियों और वेतनमानों में विभाजित किया जाता है। यह प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि समान उत्तरदायित्व वाले पदों को समान दर्जा प्राप्त हो, जिससे भर्ती और वेतन निर्धारण में न्यायसंगतता आती है। यह व्यक्ति की वरिष्ठता के स्थान पर कार्य की प्रकृति को प्राथमिकता प्रदान करती है, जो संगठन को स्पष्ट बनाती है।

240. (B) नीतिगत मार्गदर्शन और राजनीतिक दिशा।
संसदीय लोकतंत्र में मंत्री की प्राथमिक भूमिका विभाग को एक व्यापक विजन और राजनीतिक नेतृत्व प्रदान करना है। मंत्री का कार्य यह निर्धारित करना है कि सरकार के लक्ष्य क्या हैं और वे जनता की आकांक्षाओं को किस प्रकार पूर्ण करेंगे। उन्हें लोक सेवकों को स्पष्ट नीतिगत मार्गदर्शन देना चाहिए, किंतु विभाग के दैनिक और सूक्ष्म प्रशासनिक कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप से सर्वथा बचना चाहिए। जब मंत्री स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं, तो लोक सेवक अपनी विशेषज्ञता का उपयोग उन नीतियों को कुशलतापूर्वक क्रियान्वित करने में कर सकते हैं। यह स्वस्थ सीमांकन ही प्रशासनिक दक्षता और राजनीतिक जवाबदेही में संतुलन बनाता है।

241. (B) कि सार्वजनिक अधिकारी अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी हों।
सुशासन में जवाबदेही का अर्थ है कि शासन की शक्ति का प्रयोग करने वाले प्रत्येक अधिकारी को अपने निर्णयों और कृत्यों हेतु जनता या कानून के समक्ष तार्किक स्पष्टीकरण देना होगा। यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि अधिकारी अपनी शक्तियों का प्रयोग केवल जनहित में और स्थापित नियमों के अनुसार ही करें। जवाबदेही के माध्यम से त्रुटियों को सुधारा जा सकता है और लापरवाह अधिकारियों को विधिक दंड दिया जा सकता है। यह नागरिकों को यह विश्वास दिलाता है कि सरकार उनके प्रति उत्तरदायी है, जिससे प्रशासन में पारदर्शिता आती है और भ्रष्टाचार तथा मनमानी पर प्रभावी अंकुश लगता है, जो लोकतंत्र का आधार है।

242. (A) रचनात्मक सोच और समस्या-समाधान
वैचारिक मंथन एक सामूहिक रचनात्मक तकनीक है जिसका उपयोग प्रशिक्षण में प्रशिक्षुओं के भीतर नवीन और मौलिक विचारों को जागृत करने हेतु किया जाता है। इसमें प्रतिभागियों को बिना किसी आलोचना के किसी समस्या पर अधिक से अधिक विचार प्रस्तुत करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। इसका उद्देश्य लीक से हटकर चिंतन करना और जटिल प्रशासनिक चुनौतियों हेतु अभिनव समाधान खोजना है। यह पद्धति टीम वर्क को बढ़ावा देती है और प्रशिक्षुओं को विभिन्न दृष्टिकोणों से समस्याओं को देखने की क्षमता प्रदान करती है, जो आधुनिक गतिशील प्रशासन हेतु अत्यंत आवश्यक है और कार्यक्षमता में वृद्धि करती है।

243. (C) नियमन से अनुबंध प्रबंधन और वार्ता की ओर।
उदारीकरण के पश्चात लोक प्रशासन की प्रकृति में आए परिवर्तन ने लोक सेवकों हेतु नवीन कौशलों को सीखना अनिवार्य बना दिया है। अब प्रशासक केवल आदेश देने वाले अधिकारी नहीं हैं, बल्कि उन्हें निजी क्षेत्र के साथ तालमेल स्थापित करने हेतु कुशल 'अनुबंध प्रबंधक' और 'वार्ताकार' होना पड़ता है। चूंकि अब अनेक सार्वजनिक सेवाएं निजी भागीदारी के माध्यम से प्रदान की जा रही हैं, इसलिए अधिकारियों को अनुबंधों की बारीकियों को समझने, गुणवत्ता की निरंतर निगरानी करने और विभिन्न हितधारकों के बीच मध्यस्थता करने में दक्ष होना चाहिए। यह बदलाव नौकरशाही को अधिक पेशेवर, परिणाम-उन्मुख और बाजार के प्रति जागरूक बनाता है।

NODIA

244. (D) वित्तीय वर्ष के एक भाग के लिए व्यय हेतु धन निकालना।
बजट पारित होने की प्रक्रिया दीर्घकालिक होती है और कभी-कभी नए वित्तीय वर्ष के प्रारंभ तक यह पूर्ण नहीं हो पाती। ऐसी स्थिति में सरकार के पास प्रशासनिक कार्यों को जारी रखने हेतु धन का अभाव न हो, इसके लिए संविधान में 'लेखानुदान' का प्रावधान किया गया है। इसके माध्यम से संसद सरकार को बजट पारित होने तक (सामान्यतः दो माह हेतु) संचित निधि से आवश्यक धनराशि आहरण की अनुमति प्रदान कर देती है। यह केवल व्यय से संबंधित एक अग्रिम राशि है और इसमें किसी नवीन नीति या कर परिवर्तन पर चर्चा नहीं होती, जिससे सरकारी कार्यों में निरंतरता और सुगमता बनी रहती है।

245. (C) भारत के प्रधानमंत्री
लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति एक अत्यंत उच्च स्तरीय और निष्पक्ष प्रक्रिया के माध्यम से की जाती है। अधिनियम के अनुसार, चयन समिति की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। इस समिति में लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश और एक प्रतिष्ठित न्यायविद सम्मिलित होते हैं। इस बहु-सदस्यीय और संतुलित चयन समिति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लोकपाल की नियुक्ति किसी भी राजनीतिक प्रभाव से पूर्णतः मुक्त हो और संस्था की स्वतंत्रता तथा विश्वसनीयता सार्वजनिक रूप से अक्षुण्ण बनी रहे, जिससे भ्रष्टाचार के विरुद्ध कठोर कार्यवाही संभव हो सके।

246. (B) उसी स्तर पर दूसरे पद पर स्थानांतरण।
कार्मिक प्रशासन में क्षैतिज गतिशीलता का तात्पर्य किसी कर्मचारी के एक पद से दूसरे पद पर जाने से है जहाँ उसका वेतनमान, पद का दर्जा और पदानुक्रमित स्तर समान रहता है। इसे सामान्यतः 'स्थानांतरण' के रूप में जाना जाता है। इसका

है और उन्हें केवल किताबी ज्ञान तक सीमित रहने के स्थान पर एक अनुभवी प्रशासक के रूप में विकसित होने में सहायता करता है।

278. (B) खुली प्रतियोगिता और सक्षमता के आधार पर चयन।
भर्ती की योग्यता प्रणाली इस आधुनिक सिद्धांत पर आधारित है कि लोक सेवा के पदों को केवल उन व्यक्तियों द्वारा भरा जाना चाहिए जो अपनी सक्षमता और ज्ञान को विधिक रूप से प्रमाणित कर सकें। इसमें पक्षपात या राजनीतिक संबंधों हेतु कोई स्थान नहीं होता। पारदर्शी और खुली प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के माध्यम से समाज के प्रत्येक योग्य नागरिक को प्रशासन का अंग बनने का समान अवसर प्राप्त होता है। यह प्रणाली सिविल सेवा में व्यावसायिकता और तटस्थता सुनिश्चित करती है। चूँकि चयन केवल प्रतिभा के आधार पर होता है, इसलिए यह प्रशासन की कार्यक्षमता को बढ़ाता है और जनता का सरकारी संस्थाओं के प्रति विश्वास सुदृढ़ करता है।

279. (D) शुद्ध नौकरशाही विशेषताओं का एक वैचारिक निर्माण है।
मैक्स वेबर ने नौकरशाही के 'आदर्श प्रारूप' का उपयोग एक विश्लेषणात्मक उपकरण के रूप में किया था। यहाँ 'आदर्श' का अर्थ नैतिक रूप से श्रेष्ठ होना नहीं है, बल्कि यह उन शुद्धतम विशेषताओं का एक मानसिक प्रारूप है जो नौकरशाही को एक तार्किक संरचना बनाते हैं। यह वास्तविकता का सरलीकरण है ताकि वैज्ञानिक रूप से विभिन्न संगठनों की तुलना की जा सके। वेबर के अनुसार, पूर्ण श्रम विभाजन, कठोर पदानुक्रम और निर्वैयक्तिक नियम इस मॉडल के प्रमुख अंग हैं। यह वैचारिक ढांचा विद्वानों को यह समझने में सहायता करता है कि वास्तविक जीवन के संगठन इस सैद्धांतिक पूर्णता से कितना और क्यों विचलित होते हैं।

280. (A) P-4, Q-3, R-1, S-2
एफ.एम. मार्क्स ने नौकरशाही को चार प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया है। अभिभावक नौकरशाही वह है जो उत्कृष्ट ज्ञान और लोकहित की उच्च भावना से कार्य करती है। जातीय नौकरशाही में भर्ती का आधार उम्मीदवार का विशिष्ट सामाजिक वर्ग या उच्च कुल होता है। संरक्षण नौकरशाही, जिसे लूट पद्धति भी कहा जाता है, राजनीतिक वफादारी और पक्षपात पर आधारित नियुक्तियों को प्रोत्साहित करती है। अंत में, योग्यता नौकरशाही केवल खुली प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं और उम्मीदवारों की व्यक्तिगत क्षमता को सर्वोच्च महत्व प्रदान करती है। यह वर्गीकरण ऐतिहासिक और राजनीतिक संदर्भों में प्रशासनिक प्रणालियों के विकास को स्पष्टता से समझने में सहायता करता है।

281. (C) मंत्री
संसदीय व्यवस्था में 'राजनीतिक उत्तरदायित्व' का सिद्धांत यह स्पष्ट करता है कि केवल निर्वाचित प्रतिनिधि ही जनता और संसद के प्रति जवाबदेह होते हैं। विभाग के प्रमुख के रूप में मंत्री अपने मंत्रालय के प्रत्येक कार्य और निर्णय हेतु जिम्मेदार होता है, भले ही वह कार्य उसके अधीनस्थ किसी अधिकारी ने संपन्न किया हो। लोक सेवक स्थायी कार्यपालिका का अंग हैं और वे 'अनामिकता' के सिद्धांत के अंतर्गत सुरक्षित रहते हैं; उनके कार्यों की प्रशंसा या दोष मंत्री को ही स्वीकार करना पड़ता है। यदि संसद किसी नीति से असंतुष्ट है, तो उसे मंत्री से प्रश्न पूछने और उसे हटाने का विधिक अधिकार है, जो लोकतांत्रिक नियंत्रण सुनिश्चित करता है।

NODIA

282. (A) तीव्र गति और विरूपण की संभावना।
संगठन में 'ग्रेपवाइन' संचार का एक ऐसा अनौपचारिक नेटवर्क है जो सामाजिक संबंधों और व्यक्तिगत चर्चाओं के माध्यम से संचालित होता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह सूचना को औपचारिक माध्यमों की तुलना में बहुत अधिक तीव्रता से प्रसारित करता है। यद्यपि, चूँकि यह लिखित अभिलेख पर आधारित नहीं होता और अक्सर एक व्यक्ति से दूसरे तक पहुँचते समय परिवर्तित होता रहता है, इसलिए इसमें सूचना के विकृत होने या अफवाहों के रूप में फैलने का अत्यधिक जोखिम बना रहता है। प्रबंधन हेतु यह कर्मचारियों की भावनाओं को समझने में सहायता करता है किंतु त्रुटिपूर्ण सूचनाओं के कारण संगठन में भ्रम भी उत्पन्न कर सकता है।

283. (D) राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार सीमित संसाधनों का आवंटन करना।
विकास योजना का मूल उद्देश्य किसी देश के उपलब्ध सीमित वित्तीय, भौतिक और मानवीय संसाधनों का अधिकतम लाभ प्राप्त करने हेतु उनका एक नियोजित और तार्किक उपयोग करना है। चूँकि देश की समस्त समस्याओं का समाधान एक साथ संभव नहीं है, इसलिए नियोजन के माध्यम से 'राष्ट्रीय प्राथमिकताएं' निर्धारित की जाती हैं, जैसे शिक्षा या कृषि। यह संसाधनों के अपव्यय को रोकता है और उन्हें उन क्षेत्रों की ओर मोड़ता है जहाँ उनकी सर्वाधिक आवश्यकता है। इस प्रकार, विकास योजना आर्थिक वृद्धि को एक निश्चित दिशा और गति प्रदान करती है, जिससे देश का संतुलित और न्यायसंगत सामाजिक-आर्थिक उत्थान निरंतर संभव हो पाता है।

284. (B) मितव्ययिता, दक्षता और प्रभावशीलता।
निष्पादन लेखापरीक्षा पारंपरिक लेखापरीक्षा से बहुत अधिक व्यापक और आधुनिक दृष्टिकोण धारण करती है। यह केवल यह नहीं देखती कि धन नियमों के अनुसार व्यय किया गया है, बल्कि यह व्यय के तीन प्रमुख स्तंभों—मितव्ययिता, दक्षता और प्रभावशीलता—का सूक्ष्म मूल्यांकन करती है। परीक्षक यह जाँचता है कि क्या उसी कार्य को न्यून व्यय में किया जा सकता था, क्या संसाधनों का इष्टतम उपयोग हुआ और क्या व्यय ने अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया। यह प्रक्रिया सरकार को केवल वित्तीय रूप से ही नहीं, बल्कि प्रबंधकीय दृष्टि से भी जवाबदेह बनाती है, जिससे सार्वजनिक धन का वास्तविक मूल्य सुनिश्चित होता है।

285. (A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
प्रशिक्षण कोई एक बार की जाने वाली घटना नहीं, बल्कि लोक सेवक के संपूर्ण करियर के दौरान चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। आधुनिक युग में तकनीक अत्यंत तीव्रता से परिवर्तित हो रही है और शासन की चुनौतियां भी निरंतर अधिक जटिल होती जा रही हैं। यदि कोई अधिकारी अपनी भर्ती के समय प्राप्त ज्ञान तक ही सीमित रहता है, तो वह

बनाने के लिए किया गया था।
कथन II: गुटनिरपेक्षता का मूल विचार शीतयुद्ध के दौरान महाशक्ति गुटों से स्वतंत्रता बनाए रखना था।
(A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं।
(C) कथन I सत्य है, लेकिन कथन II असत्य है।
(D) कथन I असत्य है, लेकिन कथन II सत्य है।

64. द्विपक्षीय संधि और बहुपक्षीय संधि के बीच मौलिक अंतर क्या है?
(A) द्विपक्षीय संधियाँ युद्ध के बारे में हैं, जबकि बहुपक्षीय संधियाँ शांति के बारे में हैं।
(B) बहुपक्षीय संधियों के विपरीत, द्विपक्षीय संधियाँ कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होती हैं।
(C) द्विपक्षीय संधियाँ यथार्थवाद का हिस्सा हैं, जबकि बहुपक्षीय संधियाँ आदर्शवाद का हिस्सा हैं।
(D) एक द्विपक्षीय संधि में दो राज्य शामिल होते हैं, जबकि एक बहुपक्षीय संधि में दो से अधिक राज्य शामिल होते हैं।

65. एक राष्ट्र जो किसी प्रतिद्वंद्वी की बराबरी करने या उससे आगे निकलने के घोषित लक्ष्य के साथ तेजी से अपनी सैन्य क्षमताओं का निर्माण करता है, वह किसमें संलग्न है:
(A) शस्त्रों की दौड़
(B) शस्त्र नियंत्रण प्रक्रिया
(C) निरस्त्रीकरण पहल
(D) गुटनिरपेक्षता का कार्य

66. "युद्ध की रोकथाम और उन्मूलन" निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा एक प्राथमिक उद्देश्य है?
(A) शक्ति की राजनीति का यथार्थवादी सिद्धांत।
(B) अंतर्राष्ट्रीय कानून और संगठनों का विकास।
(C) शस्त्रों की दौड़ की अवधारणा।
(D) राष्ट्रवादी विचारधाराओं को बढ़ावा देना।

67. 'शीतयुद्ध के अंत' का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा है?
(A) द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण।
(B) सभी जातीय विवादों का सार्वभौमिक अंत।
(C) नई वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों का उदय।
(D) संबंधों से विचारधारा का पूर्ण लोप।

68. निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन शामिल हैं, जिन्हें अभिकथन (A) और कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है। इन दोनों कथनों का सावधानीपूर्वक परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:
अभिकथन (A): आदर्शवादी विचारक विश्व राजनीति में अंतर्राष्ट्रीय कानून और संगठनों की भूमिका का समर्थन करते हैं।
कारण (R): उनका मानना है कि इस तरह के संस्थान अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की अराजक प्रकृति को दूर कर सकते हैं और सहयोग को बढ़ावा दे सकते हैं।
(A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(D) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

69. कूटनीति के सफल उपयोग के लिए अक्सर आवश्यकता होती है:
(A) कुशल वार्ता, संचार और सामान्य आधार खोजने की इच्छा।
(B) अन्य पक्षों के राष्ट्रीय हितों की पूर्ण उपेक्षा।
(C) परमाणु युद्ध की तत्काल धमकी।
(D) सभी अंतर्राष्ट्रीय कानूनी मानदंडों की अस्वीकृति।

70. अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का अधिकार नहीं है?
(A) स्वतंत्रता और संप्रभुता
(B) क्षेत्रीय अखंडता
(C) अन्य राज्यों के साथ समानता
(D) बलपूर्वक अन्य राष्ट्रों पर अपनी विचारधारा थोपने का अधिकार

71. किसी राज्य के प्राकृतिक संसाधन, भौगोलिक आकार और जनसंख्या शक्ति के किस प्रकार के तत्वों के उदाहरण हैं?
(A) अमूर्त और वैचारिक
(B) मूर्त और मापने योग्य
(C) संचारी और बोधात्मक
(D) कानूनी और मानक

72. देश X और देश Y प्रतिद्वंद्वी हैं। देश X को Y से हमले का भय है और वह अपना रक्षा बजट बढ़ाता है। देश Y इसे खतरे के रूप में देखता है और वह भी अपना सैन्य व्यय बढ़ाता है। यह बढ़ता चक्र किसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है?
(A) सफल निरस्त्रीकरण
(B) शांति के लिए खेल सिद्धांत का अनुप्रयोग
(C) सुरक्षा दुविधा जिसके कारण शस्त्रों की दौड़ होती है
(D) एक गुटनिरपेक्ष नीति

73. 1991 के बाद दुनिया भर में लोकतांत्रिक आदर्शों और पूंजीवादी आर्थिक मॉडलों के प्रसार को किसके एक पहलू के रूप में देखा जा सकता है?
(A) शीतयुद्ध
(B) वैश्वीकरण
(C) गुटनिरपेक्षता
(D) निवारण

74. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:
सूची I: (शब्द)
P. राष्ट्रीय हित

Downloaded from www.pdf.tube

विस्तृत चर्चा हेतु सीमित समय निर्धारित होता है। जब चर्चा हेतु निर्धारित समय समाप्त होने वाला होता है, तो लोकसभा अध्यक्ष उन समस्त मांगों को, जिन पर अभी तक चर्चा संपन्न नहीं हो पाई है, एक साथ सदन के सम्मुख मतदान हेतु प्रस्तुत कर देते हैं। इस प्रक्रिया के पश्चात उन सभी मांगों को बिना किसी बहस के पारित मान लिया जाता है। यद्यपि यह विधायी कार्य पूर्ण करने हेतु आवश्यक है, किंतु इससे अनेक महत्वपूर्ण व्ययों पर सूक्ष्म संसदीय चर्चा की संभावना लुप्त हो जाती है।

294. (B) राज्य और नागरिकों के बीच संबंधों की गुणवत्ता।
सुशासन का वास्तविक अर्थ केवल फाइलों का सुचारु संचालन या आर्थिक आंकड़ों में वृद्धि नहीं है, बल्कि इसका मुख्य सार इस बात में निहित है कि शासन व्यवस्था और सामान्य नागरिक के बीच का संबंध कैसा है। सुशासन वह है जहाँ नागरिक स्वयं को शासन प्रक्रिया का केंद्र अनुभव करता है और प्रशासन उसकी गरिमा, विधिक अधिकारों और आवश्यकताओं के प्रति अत्यंत संवेदनशील होता है। जब राज्य और नागरिकों के बीच विश्वास, पारदर्शिता और निरंतर संवाद का संबंध होता है, तभी सुशासन के वास्तविक उद्देश्यों की प्राप्ति संभव होती है। यह एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ शक्ति का उपयोग केवल जनता की भलाई हेतु किया जाता है।

295. (D) पूर्ण विवेकाधिकार और अत्यधिक गोपनीयता
प्रशासन में जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु सूचना का अधिकार, सामाजिक लेखापरीक्षा और ओम्बुड्समैन जैसे तंत्र अनिवार्य हैं, क्योंकि ये कार्यों को पारदर्शी और परीक्षण के योग्य बनाते हैं। इसके विपरीत, जब किसी अधिकारी के पास 'पूर्ण विवेकाधिकार' होता है और उसके कार्यों पर कोई विधिक सीमा नहीं होती, तथा वह 'अत्यधिक गोपनीयता' के आवरण में कार्य करता है, तो जवाबदेही पूर्णतः लुप्त हो जाती है। ऐसी स्थिति भ्रष्टाचार और मनमानी को प्रोत्साहित करती है। सुशासन हेतु यह नितांत आवश्यक है कि विवेकाधिकारों को विधिक नियमों से आबद्ध किया जाए और गोपनीयता को केवल अनिवार्य सुरक्षा कारणों तक ही सीमित रखा जाए।

296. (A) यह पूछने के लिए कि प्रस्तावित दंड क्यों न अधिरोपित किया जाए।
अनुशासनात्मक प्रक्रिया में 'कारण बताओ नोटिस' प्राकृतिक न्याय का एक महत्वपूर्ण अंग है। जब किसी कर्मचारी के विरुद्ध जांच पूर्ण हो जाती है और आरोप प्रमाणित हो जाते हैं, तो उसे दंड प्रदान करने से पूर्व एक अंतिम अवसर दिया जाता है। इस नोटिस के माध्यम से कर्मचारी को यह सूचित किया जाता है कि सक्षम प्राधिकारी उसके विरुद्ध क्या दंड देने का विचार कर रहा है। कर्मचारी को यह स्पष्ट करने का अवसर प्राप्त होता है कि उसके विरुद्ध वह विशिष्ट दंड क्यों नहीं दिया जाना चाहिए। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि दंड देने का निर्णय एकतरफा न होकर पूरी तरह न्यायपूर्ण और विवेकपूर्ण हो, जो कर्मचारी के विधिक अधिकारों की रक्षा करता है।

297. (C) मैक्स वेबर
जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर ने नौकरशाही का सर्वाधिक गहन और शास्त्रीय विश्लेषण प्रस्तुत किया, जो आज भी प्रशासनिक अध्ययन का आधार बना हुआ है। उन्होंने नौकरशाही को 'आधुनिक समाज का सर्वाधिक तार्किक स्वरूप' माना और उसकी अनिवार्य विशेषताओं, जैसे पदानुक्रम, लिखित नियम, निर्वैयक्तिकता और श्रम विभाजन का वर्णन किया। वेबर ने इसे एक विधिक-तार्किक सत्ता की व्यवस्था के रूप में देखा जो आधुनिक पूंजीवादी समाज और बड़े पैमाने के राज्यों की कुशल प्रबंधन संबंधी आवश्यकताओं को पूर्ण करती है। यद्यपि उन्होंने इसके 'लौह पिंजरे' जैसे दुष्परिणामों की चेतावनी भी प्रदान की थी, किंतु नौकरशाही को एक संगठनात्मक आवश्यकता के रूप में स्थापित किया।

298. (A) आउटसोर्सिंग और सेवाओं का अनुबंध देना।
उदारीकरण ने लोक प्रशासन की कार्यशैली में 'बाजार उन्मुखता' को निरंतर बढ़ावा दिया है। अब सरकार प्रत्येक कार्य को स्वयं करने के स्थान पर उन सेवाओं को निजी क्षेत्रों या बाह्य एजेंसियों से प्राप्त करना अधिक मितव्ययी मानती है, जिसे आउटसोर्सिंग कहा जाता है। उदाहरण हेतु, स्वच्छता व्यवस्था, सुरक्षा या तकनीकी रखरखाव के कार्य अब अनुबंध के आधार पर प्रदान किए जाते हैं। इससे सरकारी विभागों का प्रशासनिक भार न्यून होता है और वे अपने मुख्य नीतिगत कार्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। यह बदलाव प्रशासन में दक्षता बढ़ाने और व्यय कम करने का एक आधुनिक मार्ग है, जहाँ सरकार संचालक के बजाय कुशल प्रबंधक बनती है।

299. (D) व्यय स्थापित नियमों और स्वीकृतियों के अनुरूप है।
नियमितता लेखापरीक्षा वित्तीय प्रशासन की एक बुनियादी और अनिवार्य प्रक्रिया है। इसका मुख्य उद्देश्य यह जाँचना है कि क्या सरकार द्वारा किया गया व्यय संसद द्वारा प्रदान की गई स्वीकृति और स्थापित वित्तीय नियमों के पूर्णतः अंतर्गत है। परीक्षक यह सूक्ष्मता से देखता है कि क्या प्रत्येक व्यय हेतु उचित साक्ष्य और रसीदें उपलब्ध हैं और क्या उस व्यय को करने हेतु संबंधित अधिकारी के पास आवश्यक विधिक शक्तियां थीं। यह व्यय की बुद्धिमत्ता या परिणामों के स्थान पर उसके 'विधिक अनुपालन' पर अधिक ध्यान केंद्रित करती है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि सार्वजनिक धन का प्रयोग केवल अधिकृत और नियमित तरीके से ही किया जाए।

300. (B) अन्ना हजारे
भारत में लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के पारित होने के पीछे 2011 में अन्ना हजारे के नेतृत्व में हुए भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की निर्णायक भूमिका रही है। इस ऐतिहासिक जन आंदोलन ने संपूर्ण देश का ध्यान सार्वजनिक जीवन में व्याप्त भ्रष्टाचार की ओर आकर्षित किया और सरकार पर एक सुदृढ़ भ्रष्टाचार विरोधी कानून निर्मित करने का भारी दबाव डाला। गांधीवादी मूल्यों पर आधारित इस आंदोलन ने लोकपाल की अवधारणा को सामान्य जन तक पहुँचाया और इसे एक प्रमुख राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया। इसी प्रबल जन दबाव के परिणामस्वरूप संसद को अंततः लोकपाल अधिनियम पारित करना पड़ा, जो भारत के विधिक ढांचे में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

NODIA

(D) मानव प्रकृति रणनीतिक खेलों और सिद्धांत के लाभों का उत्पाद है।

41. नाटो और वारसॉ पैक्ट जैसे सैन्य गठबंधनों की स्थापना किस ऐतिहासिक काल की प्रमुख विशेषता थी?
(A) वैश्वीकरण का युग
(B) शीतयुद्ध के बाद का युग
(C) शीतयुद्ध
(D) गुटनिरपेक्ष आंदोलन

42. अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में 'शक्ति' की अवधारणा मुख्य रूप से किसे संदर्भित करती है?
(A) दूसरों के व्यवहार को प्रभावित करने की राज्य की क्षमता।
(B) संयुक्त राष्ट्र और उसके चार्टर द्वारा प्रदान किया गया कानूनी अधिकार।
(C) किसी विशिष्ट राष्ट्रीय विचारधारा की पूर्ण नैतिक श्रेष्ठता।
(D) एक संप्रभु देश का कुल भूमि क्षेत्र और भौगोलिक विशेषताएं।

43. निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय शक्ति के अमूर्त तत्व का एक उदाहरण है?
(A) सशस्त्र बलों का आकार
(B) कच्चे तेल के भंडार की मात्रा
(C) उन्नत लड़ाकू विमानों की संख्या
(D) राजनीतिक नेतृत्व की गुणवत्ता

44. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:
सूची I: (अवधारणा)
P. निरस्त्रीकरण
Q. निवारण
R. कूटनीति
S. हस्तक्षेप
सूची II: (विवरण)
1. प्रतिशोध की धमकी देकर किसी कार्रवाई को रोकना
2. शस्त्रों की कमी या उन्मूलन
3. दूसरे राज्य के मामलों में बलपूर्वक हस्तक्षेप
4. आधिकारिक एजेंटों के माध्यम से राज्यों के बीच संबंधों का संचालन
कूट:
(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-2, Q-1, R-4, S-3
(C) P-3, Q-4, R-1, S-2
(D) P-2, Q-3, R-4, S-1

45. 'शीतयुद्ध के अंत' को निम्नलिखित में से किस परिणाम के साथ सबसे निकटता से जोड़ा जाता है?
(A) एक स्थिर द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण।
(B) गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पूर्ण विघटन।
(C) वैश्विक शक्ति संतुलन में एक मौलिक बदलाव।
(D) दुनिया भर में सभी जातीय विवादों की पूर्ण समाप्ति।

46. अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का कौन सा सिद्धांत प्रमुख शक्तियों के बीच युद्ध रोकने में अंतर्राष्ट्रीय कानून की प्रभावशीलता के बारे में सर्वाधिक संशयवादी होगा?
(A) आदर्शवाद
(B) संचार सिद्धांत
(C) निर्णय-प्रक्रिया सिद्धांत
(D) यथार्थवाद

47. राष्ट्रीय हित के निर्धारण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन I: राष्ट्रीय हित का निर्धारण एक वस्तुनिष्ठ, वैज्ञानिक प्रक्रिया है जो राजनीतिक प्रभाव से मुक्त है।
कथन II: इसमें अक्सर विभिन्न घरेलू अभिनेताओं और संस्थानों के बीच बहस और समझौते की एक जटिल प्रक्रिया शामिल होती है।
(A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं।
(C) कथन I सत्य है, लेकिन कथन II असत्य है।
(D) कथन I असत्य है, लेकिन कथन II सत्य है।

48. अन्य राज्यों के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप न करने का राज्य का कर्तव्य अंतर्राष्ट्रीय कानून के किस मौलिक सिद्धांत का आधार है?
(A) निवारण का सिद्धांत
(B) संप्रभुता का सिद्धांत
(C) शस्त्रों की दौड़ का सिद्धांत
(D) वैश्वीकरण का सिद्धांत

49. किसी राज्य द्वारा शक्ति के उपयोग की प्राथमिक सीमाओं में से एक है:
(A) किसी भी संभावित प्रतिद्वंद्वी की अनुपस्थिति।
(B) अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अन्य राज्यों की कार्रवाइयां और संभावित प्रतिक्रियाएं।
(C) विचारधारा पर पूर्ण निर्भरता।
(D) राष्ट्रीय हित की कमी।

50. आदर्शवादी दृष्टिकोण के प्रमुख तर्कों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. शक्ति की राजनीति और अराजकता का महत्व।
2. राज्यों के बीच हितों के सामंजस्य की संभावना।
3. अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों और कानून की प्रभावकारिता में विश्वास।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3

Click Here to Buy book on Amazon

(C) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(D) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

9. निम्नलिखित में से किसे छोड़कर सभी को राष्ट्रीय शक्ति का तत्व माना जाता है:
(A) सैन्य शक्ति और तकनीकी प्रगति।
(B) आर्थिक क्षमता और संसाधन संपन्नता।
(C) नीति-निर्माण में विचारधारा की पूर्ण अनुपस्थिति।
(D) भौगोलिक स्थिति और जनसंख्या का आकार।

10. अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संचार दृष्टिकोण राज्यों के बीच अंतःक्रियाओं में किस केंद्रीय तत्व पर ध्यान केंद्रित करता है?
(A) सूचना प्रवाह और धारणा की विशिष्ट प्रक्रियाएं।
(B) विरोधी सैन्य बलों का रणनीतिक संतुलन।
(C) वैश्विक आर्थिक व्यापार प्रणाली की संरचना।
(D) अंतर्राष्ट्रीय संधियों को नियंत्रित करने वाला कानूनी ढांचा।

11. एक राज्य द्वारा अपनी विस्तारवादी विदेश नीति को एक विशेष राजनीतिक व्यवस्था फैलाने के मिशन का दावा करके उचित ठहराना किसका उदाहरण है?
(A) विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए कूटनीति का उपयोग।
(B) अंतर्राष्ट्रीय संधि कानून का अनुप्रयोग।
(C) पारंपरिक शस्त्र नियंत्रण की प्रक्रिया।
(D) राष्ट्रीय हित को आकार देने और उसे उचित ठहराने में विचारधारा की भूमिका।

12. राज्यों के भीतर या उनके बीच पहचान, भाषा और सांस्कृतिक स्वायत्तता को लेकर विवादों से उत्पन्न होने वाले संघर्ष को किस प्रकार के संघर्ष के रूप में वर्गीकृत करना सबसे उपयुक्त है?
(A) विशुद्ध रूप से आर्थिक संघर्ष
(B) जातीय विवाद
(C) परमाणु युद्ध की स्थिति
(D) व्यवस्थागत संघर्ष

13. परमाणु निवारण के पीछे प्राथमिक अवधारणा क्या है?
(A) यह विश्वास कि एक राज्य अपने मुख्य आधारभूत ढांचे को न्यूनतम क्षति पहुँचाकर परमाणु युद्ध जीत सकता है।
(B) विश्व स्तर पर परमाणु शस्त्रागार की सभी श्रेणियों को पूरी तरह से समाप्त करने की आधिकारिक प्रक्रिया।
(C) अस्वीकार्य प्रतिशोधात्मक क्षति पहुँचाने की क्षमता बनाए रखकर हमलों को रोकना।
(D) पारंपरिक युद्धों के दौरान छोटे, सामरिक परमाणु हथियारों के उपयोग की विशिष्ट रणनीति।

14. अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के दृष्टिकोणों के संबंध में सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:
सूची I: (दृष्टिकोण)
P. यथार्थवादी
Q. आदर्शवादी
R. खेल सिद्धांत
S. निर्णय-प्रक्रिया
सूची II: (मुख्य अवधारणा)
1. अंतर्राष्ट्रीय कानून और नैतिकता
2. नौकरशाही राजनीति और धारणा
3. शक्ति और राष्ट्रीय हित
4. रणनीतिक अंतःक्रिया और लाभ
कूट:
(A) P-3, Q-1, R-4, S-2
(B) P-1, Q-3, R-2, S-4
(C) P-3, Q-1, R-2, S-4
(D) P-2, Q-4, R-3, S-1

NODIA

15. शस्त्रों की दौड़ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन I: शस्त्रों की दौड़ दो या दो से अधिक राज्यों द्वारा श्रेष्ठ हथियार प्रणालियों का प्रतिस्पर्धी अधिग्रहण है।
कथन II: शस्त्रों की दौड़ की गतिशीलता अक्सर सुरक्षा दुविधा से प्रेरित होती है, जहाँ एक राज्य के सुरक्षात्मक उपायों को दूसरे द्वारा खतरे के रूप में देखा जाता है।
(A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं।
(C) कथन I सत्य है, लेकिन कथन II असत्य है।
(D) कथन I असत्य है, लेकिन कथन II सत्य है।

16. अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए निम्नलिखित में से किसे एक विधि माना जाता है?
(A) सैन्य हस्तक्षेप
(B) राजनयिक वार्ता
(C) आर्थिक प्रतिबंध
(D) शस्त्रों की दौड़

17. शीतयुद्ध काल मुख्य रूप से किसके द्वारा पहचाना गया था?
(A) कई प्रतिस्पर्धी महान शक्तियों के साथ एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था।
(B) दो महाशक्ति-नेतृत्व वाले वैचारिक गुटों के बीच एक द्विध्रुवीय टकराव।
(C) निरस्त्रीकरण और सामूहिक सुरक्षा पर वैश्विक सहमति।
(D) सभी प्रमुख राज्यों द्वारा गुटनिरपेक्षता को सार्वभौमिक रूप से अपनाना।

18. गुटनिरपेक्षता की नीति का मूल सिद्धांत क्या है?
(A) किसी भी प्रमुख शक्ति गुट के साथ या उसके विरुद्ध औपचारिक रूप से शामिल होने से इनकार करना।
(B) सुरक्षा के लिए सैन्य गठबंधन में अनिवार्य रूप से शामिल होना।
(C) अलगाववाद और अंतर्राष्ट्रीय मामलों से पूर्ण वापसी का प्रयास।
(D) एकल वैश्विक विचारधारा को बढ़ावा देना।

शीघ्र ही अप्रासंगिक हो जाएगा। इसलिए, निरंतर अंतराल पर पुनश्चर्या पाठ्यक्रम और नवीन कार्यपद्धतियों का प्रशिक्षण अनिवार्य है ताकि कर्मचारी नवीन परिस्थितियों और जनता की बदलती अपेक्षाओं के अनुसार अपनी क्षमताओं को उन्नत कर सके। निरंतर सीखना ही प्रशासनिक कार्यकुशलता को जीवित रखता है।

286. (D) प्रणालीगत भ्रष्टाचार
प्रणालीगत भ्रष्टाचार वह स्थिति है जहाँ भ्रष्टाचार केवल कतिपय व्यक्तियों तक सीमित न रहकर संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था का एक अनिवार्य हिस्सा बन जाता है। यहाँ नियम और प्रक्रियाएं इस प्रकार विकृत हो जाती हैं कि सामान्य कार्य निष्पादन हेतु भी रिश्वत देना एक अघोषित अनिवार्यता बन जाती है। ऐसे प्रकरणों में भ्रष्टाचार नीचे से ऊपर तक संगठित होता है, जिससे ईमानदारी से कार्य करना लगभग असंभव हो जाता है। यह प्रशासन की नींव को खोखला कर देता है और विकास के समस्त प्रयासों को विफल बनाता है। इसे केवल व्यक्तियों को हटाकर नहीं, बल्कि पूरी प्रणाली में व्यापक संरचनात्मक सुधारों और पारदर्शिता के माध्यम से ही दूर किया जा सकता है।

287. (A) किसी तीसरे पक्ष से संबंधित सूचना का खुलासा करने के पी.आई.ओ. के निर्णय के विरुद्ध।
सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत 'तृतीय पक्ष' वह व्यक्ति या संस्था है जो न तो आवेदक है और न ही वह सार्वजनिक प्राधिकरण। जब कोई आवेदक ऐसी सूचना की मांग करता है जो किसी तीसरे पक्ष की गोपनीय जानकारी हो सकती है, तो जन सूचना अधिकारी को उस पक्ष से उसकी राय अनिवार्यतः पूछनी पड़ती है। यदि अधिकारी उस पक्ष की आपत्ति के उपरांत भी सूचना देने का निर्णय लेता है, तो उस तीसरे पक्ष को यह विधिक अधिकार है कि वह उस निर्णय के विरुद्ध अपील करे। यह प्रावधान व्यक्तिगत गोपनीयता और व्यावसायिक हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है, ताकि पारदर्शिता के नाम पर किसी निर्दोष पक्ष के विधिक अधिकारों का उल्लंघन न हो।

288. (B) कार्यपालिका के विरुद्ध विधायिका।
ओम्बुड्समैन की संस्था का निर्माण ऐतिहासिक रूप से विधायिका द्वारा एक प्रहरी के रूप में किया गया था ताकि वह कार्यपालिका की शक्तियों पर प्रभावी अंकुश लगा सके। यद्यपि विधायिका कानून निर्मित करती है, किंतु उसे क्रियान्वित करने का कार्य प्रशासकों का होता है, जहाँ वे शक्तियों का दुरुपयोग कर सकते हैं। ओम्बुड्समैन विधायिका की ओर से स्वतंत्र रूप से कार्य करता है और नागरिकों की उन व्यथाओं की जांच करता है जहाँ प्रशासन ने अन्याय या लापरवाही की हो। वह अपनी रिपोर्ट सीधे विधायिका को सौंपता है। इस प्रकार, यह संस्था विधायी नियंत्रण को सशक्त बनाती है और यह सुनिश्चित करती है कि कार्यपालिका जनता के प्रति जवाबदेह बनी रहे।

289. (B) योग्यता और श्रेष्ठ निष्पादन को हतोत्साहित करता है।
पदोन्नति हेतु केवल वरिष्ठता के सिद्धांत पर निर्भर रहने की सबसे बड़ी न्यूनता यह है कि यह प्रतिभावान और अधिक परिश्रमी कर्मचारियों को हतोत्साहित करती है। जब एक कुशल युवा कर्मचारी यह देखता है कि उसके उत्कृष्ट कार्य के उपरांत भी पदोन्नति केवल सेवा के वर्षों के आधार पर प्राप्त होगी, तो उसमें नवाचार करने या अतिरिक्त प्रयास करने की प्रेरणा लुप्त हो जाती है। यह प्रणाली संगठन को औसत दर्जे का बना सकती है क्योंकि इसमें श्रेष्ठता के स्थान पर केवल 'प्रतीक्षा' को पुरस्कृत किया जाता है। एक स्वस्थ संगठन हेतु यह आवश्यक है कि वह अनुभव के साथ-साथ योग्यता और कार्यक्षमता को भी उचित स्थान प्रदान करे।

290. (A) केवल 2
संचार एक सक्रिय और गतिशील दो-तरफा प्रक्रिया है, जिसमें प्रेषक द्वारा संदेश प्रेषण के पश्चात प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया या प्रतिपुष्टि अनिवार्य होती है। प्रतिपुष्टि के अभाव में प्रेषक कभी यह नहीं जान सकता कि उसका संदेश सटीक ढंग से समझा गया है या नहीं। इसके विपरीत, 'शोर' संचार में कभी सहायक नहीं होता; यह एक व्यवधान है जो सूचना के प्रवाह को अवरुद्ध करता है और संदेश के वास्तविक अर्थ को विकृत कर देता है। संचार की प्रभावशीलता केवल सूचना भेजने में नहीं, बल्कि उसे सही रूप में साझा करने और समझने में निहित है। इसलिए, किसी भी सफल संगठन हेतु एक सुदृढ़ प्रतिपुष्टि तंत्र का होना नितांत आवश्यक है।

291. (C) टीम प्रबंधन
प्रबंधकीय ग्रिड प्रारूप में 'टीम प्रबंधन' शैली को नेतृत्व का सर्वोत्तम स्वरूप माना गया है। इस शैली में नेता एक ओर अपने कर्मचारियों की भावनाओं, विकास और आपसी संबंधों के प्रति अत्यंत संवेदनशील होता है, तो दूसरी ओर वह संगठन के लक्ष्यों और उत्पादन के प्रति भी पूरी तरह समर्पित रहता है। यहाँ कार्य और मानवीय संबंधों के बीच कोई टकराव नहीं होता, बल्कि दोनों एक-दूसरे के पूरक बनते हैं। कर्मचारी स्वयं को संगठन का अभिन्न अंग अनुभव करते हैं और सामूहिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु स्वेच्छा से कठोर परिश्रम करते हैं। यह शैली उच्च मनोबल, प्रतिबद्धता और निरंतर उत्पादकता सुनिश्चित करने हेतु वैश्विक स्तर पर जानी जाती है।

292. (D) परिवर्तन और आधुनिकीकरण का अभिकर्ता।
विकास प्रशासन में नौकरशाही की भूमिका पारंपरिक 'शासक' से परिवर्तित होकर एक सक्रिय 'परिवर्तन अभिकर्ता' की होनी चाहिए। विकासशील देशों में समाज को पिछड़ेपन से निकालकर आधुनिकता और समृद्धि की ओर अग्रसर करने की जिम्मेदारी प्रशासन पर होती है। इसका अर्थ है कि नौकरशाहों को केवल फाइलों का निस्तारण नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें नवीन तकनीक अपनाने, सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध चेतना जागृत करने और विकास परियोजनाओं को मिशन मोड में पूर्ण करने हेतु नेतृत्व करना चाहिए। उन्हें नवाचारों को प्रोत्साहित करना चाहिए और जनता के साथ मिलकर एक ऐसी प्रगतिशील कार्य संस्कृति विकसित करनी चाहिए जो राष्ट्र निर्माण में सहायक हो।

293. (C) अवशेष मांगों को एक साथ मतदान के लिए रखना।
'गिलोटिन' संसदीय बजटीय प्रक्रिया का एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग समय की कमी के कारण किया जाता है। बजट सत्र के दौरान प्रत्येक मंत्रालय की अनुदान की मांगों पर

Downloaded from www.pdf.tube

2. राजनयिक संबंधों को विच्छेद करना
3. मध्यस्थता या कानूनी अधिनिर्णय
4. सीमित सैन्य हस्तक्षेप

(A) 1, 3, 2, 4
(B) 3, 1, 2, 4
(C) 1, 2, 3, 4
(D) 3, 2, 4, 1

31. खेल सिद्धांत में, वह स्थिति जहाँ एक अभिनेता का लाभ दूसरे अभिनेता की हानि के बिल्कुल बराबर होता है, कहलाती है:
(A) शून्य-योग खेल
(B) गैर-शून्य-योग खेल
(C) सकारात्मक-योग खेल
(D) संचार खेल

32. राष्ट्रीय हित की 'धारणा' महत्वपूर्ण है क्योंकि:
(A) यह हमेशा वस्तुनिष्ठ और पूर्वाग्रह से मुक्त होती है।
(B) यह निर्धारित करती है कि नीति निर्माता घटनाओं की व्याख्या कैसे करते हैं और प्रतिक्रियाएँ कैसे तैयार करते हैं।
(C) यह स्थिर है और नेताओं द्वारा इसे बदला नहीं जा सकता है।
(D) यह केवल आदर्शवादी सिद्धांत में प्रासंगिक है।

33. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन I: शीतयुद्ध के अंत के परिणामस्वरूप कम से कम अस्थाई रूप से एक एकध्रुवीय अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बनी।
कथन II: वैश्वीकरण ने बिना किसी अपवाद के राष्ट्र-राज्य की पूर्ण संप्रभुता को सुदृढ़ किया है।
(A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं।
(C) कथन I सत्य है, लेकिन कथन II असत्य है।
(D) कथन I असत्य है, लेकिन कथन II सत्य है।

34. निम्नलिखित में से कौन सा कूटनीति का प्राथमिक कार्य नहीं है?
(A) वार्ता
(B) प्रतिनिधित्व
(C) प्रतिवेदन और अवलोकन
(D) एकपक्षीय सैन्य विजय

35. एक विद्वान जो यह तर्क देता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति व्यवस्था की संरचना, विशेष रूप से शक्ति के वितरण द्वारा आकार लेती है, वह किस दृष्टिकोण का उपयोग कर रहा है?
(A) निर्णय-प्रक्रिया दृष्टिकोण
(B) संचार दृष्टिकोण
(C) व्यवस्था दृष्टिकोण
(D) आदर्शवादी दृष्टिकोण

36. अंतर्राष्ट्रीय कानून का वह सिद्धांत कि राज्य उन संधियों का सम्मान करने के लिए बाध्य हैं जिन पर उन्होंने हस्ताक्षर किए हैं, कहलाता है:
(A) जस कोजेंस
(B) पाक्टा संट सरवेंडा
(C) रेबस सिक स्टैंटिबस
(D) एरगा ओम्नेस

37. एंथ्रेक्स या सरीन गैस जैसे सामूहिक विनाश के हथियारों से लड़ा जाने वाला युद्ध किस रूप में वर्गीकृत किया जाएगा?
(A) पारंपरिक युद्ध
(B) जातीय विवाद
(C) व्यवस्थागत युद्ध
(D) जैव-रासायनिक युद्ध

38. निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन शामिल हैं, जिन्हें अभिकथन (A) और कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है। इन दोनों कथनों का सावधानीपूर्वक परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:
अभिकथन (A): वैश्वीकरण की प्रक्रिया राष्ट्र-राज्यों के पारंपरिक अधिकार और स्वायत्तता को चुनौती देती है।
कारण (R): पूंजी, सूचना और संस्कृति के अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के उदय के साथ, अपने घरेलू मामलों पर राज्य के नियंत्रण को सीमित कर सकते हैं।
(A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(D) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

39. 'शस्त्र नियंत्रण' और 'निरस्त्रीकरण' के बीच मुख्य अंतर यह है कि:
(A) निरस्त्रीकरण एक यथार्थवादी अवधारणा है, जबकि शस्त्र नियंत्रण एक आदर्शवादी अवधारणा है।
(B) शस्त्र नियंत्रण केवल परमाणु हथियारों पर लागू होता है, जबकि निरस्त्रीकरण सभी हथियारों पर लागू होता है।
(C) शस्त्र नियंत्रण हथियारों के प्रबंधन पर केंद्रित है, जबकि निरस्त्रीकरण का उद्देश्य उन्हें कम करना या समाप्त करना है।
(D) कोई अंतर नहीं है; ये शब्द एक-दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त किए जा सकते हैं।

NODIA

40. निम्नलिखित में से कौन मानव प्रकृति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में इसकी भूमिका पर आदर्शवादी दृष्टिकोण का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है?
(A) मानव प्रकृति मौलिक रूप से अच्छी है और सहयोग करने में सक्षम है।
(B) मानव प्रकृति स्वाभाविक रूप से स्वार्थी है और शक्ति-प्राप्ति द्वारा संचालित है।
(C) अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के अध्ययन के लिए मानव प्रकृति अप्रासंगिक है।

19. दुनिया भर में अर्थव्यवस्थाओं, संस्कृतियों और समाजों की बढ़ती परस्पर संबद्धता, जो राष्ट्रीय सीमाओं के महत्व को कम करती है, उसे सबसे अच्छी तरह वर्णित किया जाता है:
(A) हस्तक्षेप
(B) निवारण
(C) वैश्वीकरण
(D) राष्ट्रीय हित

20. अंतर्राष्ट्रीय कानून के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. इसमें राज्यों के अधिकार और कर्तव्य शामिल हैं।
2. यह संधियों के लिए कानूनी ढांचे को संबोधित करता है।
3. यह मुख्य रूप से एक ही राज्य की आंतरिक राजनीति से संबंधित है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3

21. पारंपरिक अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत निम्नलिखित में से किसे राज्य का मौलिक अधिकार नहीं माना जाता है?
(A) संप्रभु समानता का अधिकार।
(B) क्षेत्रीय अखंडता का अधिकार।
(C) अन्य संप्रभु राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार।
(D) आत्मरक्षा का अधिकार।

22. अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में 'हस्तक्षेप' की अवधारणा का तात्पर्य है:
(A) अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर करने और उसकी पुष्टि करने की प्रक्रिया।
(B) एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य के आंतरिक मामलों में बलपूर्वक हस्तक्षेप।
(C) संचार के लिए राजनयिक चैनलों का उपयोग।
(D) अंतर्राष्ट्रीय संगठन में स्वैच्छिक भागीदारी।

23. नियमों का वह समूह जो राज्यों के बीच समझौतों के निर्माण, व्याख्या और समाप्ति को नियंत्रित करता है, उसे कहा जाता है:
(A) संचार सिद्धांत
(B) राष्ट्रीय हित सिद्धांत
(C) निवारण नीति
(D) संधि कानून

24. एक राजनीतिक नेता कहता है, "हमारी विदेश नीति केवल आदर्शों के बारे में नहीं है; यह एक असुरक्षित विश्व में हमारे राष्ट्र को सुरक्षित करने के लिए शक्ति के अधिग्रहण और संरक्षण के बारे में है।" यह कथन किस दृष्टिकोण के सिद्धांतों को सबसे निकटता से दर्शाता है?
(A) यथार्थवादी दृष्टिकोण
(B) आदर्शवादी दृष्टिकोण
(C) संचार दृष्टिकोण
(D) व्यवस्था दृष्टिकोण

25. गलत युग्म की पहचान कीजिए।
(A) शक्ति का मूर्त तत्व : सैन्य उपकरण
(B) शक्ति का अमूर्त तत्व : राष्ट्रीय मनोबल
(C) शक्ति की सीमा : निरंतर शस्त्रों की दौड़
(D) शक्ति का उपयोग : बल प्रयोग

26. जब कोई सरकार अपनी विदेश नीति में विदेशों में महत्वपूर्ण तेल भंडारों तक पहुंच सुनिश्चित करने को प्राथमिकता देती है, तो वह मुख्य रूप से अपने किस बोध पर कार्य कर रही होती है?
(A) राष्ट्रीय हित
(B) वैचारिक कर्तव्य
(C) निरस्त्रीकरण के प्रति प्रतिबद्धता
(D) गुटनिरपेक्षता का पालन

27. अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में 'विचारधारा' शब्द का तात्पर्य है:
(A) राज्य का कुल सकल घरेलू उत्पाद और आर्थिक उत्पादन।
(B) राष्ट्र की स्थायी सेना में सैनिकों की कुल संख्या।
(C) दो या दो से अधिक संप्रभु राज्यों के बीच हस्ताक्षरित एक औपचारिक संधि।
(D) राजनीतिक सिद्धांत बनाने वाले विचारों और मूल्यों का एक व्यवस्थित निकाय।

28. अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में युद्ध की प्रकृति के बारे में सही कथन की पहचान कीजिए।
(A) युद्ध हमेशा एक ही, आसानी से पहचाने जाने वाले कारक के कारण होते हैं।
(B) युद्ध की प्रकृति और कारण राजनीतिक, आर्थिक या वैचारिक हो सकते हैं।
(C) अंतर्राष्ट्रीय कानून संघर्ष के सभी रूपों को समाप्त करने में पूरी तरह सफल रहा है।
(D) सभी आधुनिक संघर्षों को परमाणु युद्ध के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

29. 'शस्त्र नियंत्रण' शब्द को सबसे अच्छी तरह इस प्रकार समझा जा सकता है:
(A) सभी हथियारों का पूर्ण उन्मूलन।
(B) सैन्य व्यय में एकपक्षीय वृद्धि।
(C) कुछ हथियारों के उत्पादन, तैनाती या उपयोग को विनियमित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय या द्विपक्षीय समझौते।
(D) स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक शस्त्रों की दौड़ को बढ़ावा देना।

30. निम्नलिखित कार्यों को विवाद निपटान के प्रयासों के तर्कसंगत क्रम में व्यवस्थित कीजिए, जो सर्वाधिक शांतिपूर्ण से कम शांतिपूर्ण की ओर बढ़ रहे हों:
1. राजनयिक विरोध और वार्ता

Click Here to Buy book on Amazon

51. 'जैव-रासायनिक युद्ध' एक ऐसा संघर्ष है जिसमें किसका उपयोग शामिल होता है:
(A) पारंपरिक तोपखाने और टैंक।
(B) प्रचार और वैचारिक संदेश।
(C) जीवित जीव या उनके विषाक्त उत्पाद जिनसे मृत्यु हो सकती है।
(D) आर्थिक प्रतिबंध और व्यापार नाकाबंदी।

52. राष्ट्रीय हित को बढ़ावा देना विभिन्न माध्यमों से प्राप्त किया जा सकता है। राष्ट्रीय हित को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा 'कठोर शक्ति' का उपकरण है?
(A) सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम
(B) सैन्य बल या बल प्रयोग की धमकी
(C) राजनयिक वार्ता
(D) विकास के लिए विदेशी सहायता

53. सूचना का प्रवाह कैसे होता है, धारणाएं कैसे बनती हैं, और गलतफहमी कैसे संघर्ष की ओर ले जाती है, इसका अध्ययन किस दृष्टिकोण का केंद्र है?
(A) यथार्थवादी दृष्टिकोण
(B) व्यवस्था दृष्टिकोण
(C) आदर्शवादी दृष्टिकोण
(D) संचार दृष्टिकोण

54. द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ के नेतृत्व वाले गुट और संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाले गुट के बीच तीव्र भू-राजनीतिक तनाव की अवधि को कहा जाता है:
(A) शीतयुद्ध
(B) वैश्वीकरण युग
(C) निरस्त्रीकरण का युग
(D) हस्तक्षेप का युग

55. सही युग्म की पहचान कीजिए।
(A) आदर्शवाद : अपरिहार्य संघर्ष पर ध्यान
(B) यथार्थवाद : अंतर्राष्ट्रीय कानून और नैतिकता पर ध्यान
(C) खेल सिद्धांत : रणनीतिक स्थितियों में तर्कसंगत निर्णय लेने पर ध्यान
(D) व्यवस्था सिद्धांत : नेताओं के व्यक्तिगत मनोविज्ञान पर ध्यान

56. यह तर्क कि विदेश नीति अक्सर विभिन्न सरकारी एजेंसियों और विभागों के बीच सौदेबाजी और समझौते का परिणाम होती है, निर्णय-प्रक्रिया दृष्टिकोण के किस मॉडल का केंद्र है?
(A) नौकरशाही राजनीति मॉडल
(B) तर्कसंगत अभिनेता मॉडल
(C) आदर्शवादी मॉडल
(D) व्यवस्थागत मॉडल

57. अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में गठबंधन आमतौर पर किस प्राथमिक उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं?
(A) वैश्विक निरस्त्रीकरण को बढ़ावा देना।
(B) सदस्य राज्यों के बीच गुटनिरपेक्षता को प्रोत्साहित करना।
(C) राष्ट्र-राज्य की अवधारणा को समाप्त करना।
(D) किसी सामान्य खतरे के विरुद्ध सामूहिक सुरक्षा या शक्ति को बढ़ाना।

58. यथार्थवादी परिप्रेक्ष्य से, 'शस्त्रों की दौड़' की घटना का प्राथमिक कारण क्या है?
(A) अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की अराजक संरचना और उससे उत्पन्न सुरक्षा दुविधा।
(B) मानव प्रकृति की अंतर्निहित अच्छाई।
(C) अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण संधियों की बाध्यकारी प्रकृति।
(D) विश्वास बढ़ाने में वैश्विक संचार की सफलता।

59. अंतर्राष्ट्रीय कानून के संदर्भ में, 'हस्तक्षेप' को सामान्यतः किसी राज्य के किसका उल्लंघन माना जाता है?
(A) संधि दायित्व
(B) गठबंधन प्रतिबद्धताएं
(C) संप्रभुता
(D) निवारण की स्थिति

60. निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य की शक्ति पर सीमा का प्रतिनिधित्व करता है?
(A) एक शक्तिशाली विरोधी गठबंधन का अस्तित्व।
(B) एक बड़ी और तकनीकी रूप से उन्नत सेना।
(C) एक मजबूत और बढ़ती अर्थव्यवस्था।
(D) राष्ट्रीय एकता की तीव्र भावना।

61. अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विचारधारा के बारे में गलत कथन की पहचान कीजिए।
(A) विचारधारा विश्व की घटनाओं की व्याख्या के लिए एक रूपरेखा प्रदान कर सकती है।
(B) विचारधारा का उपयोग राज्य की विदेश नीति के कार्यों को वैध बनाने के लिए किया जा सकता है।
(C) प्रतिस्पर्धी विचारधाराएं शीतयुद्ध की एक केंद्रीय विशेषता थीं।
(D) आधुनिक युग में राष्ट्रीय हित के निर्धारण में विचारधारा की कोई भूमिका नहीं है।

62. विवाद करने वाले राज्यों के बीच वार्ता को सुविधाजनक बनाने के लिए तीसरे पक्ष का उपयोग शांतिपूर्ण समाधान की किस पद्धति का एक उदाहरण है?
(A) वार्ता
(B) मध्यस्थता
(C) हस्तक्षेप
(D) निवारण

63. गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन I: गुटनिरपेक्ष आंदोलन का निर्माण अमेरिका और सोवियत संघ के प्रतिद्वंद्वी के रूप में एक तीसरा सैन्य गुट

Downloaded from www.pdf.tube

अध्याय 07
अंतरराष्ट्रीय संबंध

1. अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन का कौन सा दृष्टिकोण शांति की कुंजी के रूप में नैतिक सिद्धांतों, अंतर्राष्ट्रीय कानून और संगठनों पर बल देता है?
(A) यथार्थवादी दृष्टिकोण
(B) आदर्शवादी दृष्टिकोण
(C) व्यवस्था दृष्टिकोण
(D) खेल सिद्धांत दृष्टिकोण

2. अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का यथार्थवादी दृष्टिकोण मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय अभिनेता और विश्लेषण की इकाई के रूप में केंद्रित करता है?
(A) संप्रभु राज्य
(B) अंतर्राष्ट्रीय संगठन
(C) गैर-सरकारी संगठन
(D) बहुराष्ट्रीय निगम

3. अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के व्यवस्था दृष्टिकोण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन I: यह अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का समग्र रूप से विश्लेषण करता है, जो इसकी संरचना और इसकी घटक इकाइयों के बीच अंतःक्रियाओं पर केंद्रित होता है।
कथन II: यह मुख्य रूप से व्यक्तिगत नेताओं की आंतरिक मनोवैज्ञानिक प्रेरणाओं से संबंधित है।
(A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं।
(C) कथन I सत्य है, लेकिन कथन II असत्य है।
(D) कथन I असत्य है, लेकिन कथन II सत्य है।

4. निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में खेल सिद्धांत दृष्टिकोण के मुख्य फोकस का सबसे अच्छा वर्णन करता है?
(A) विभिन्न राजनयिक संचारों के ऐतिहासिक वृत्तांतों का विश्लेषण करना।
(B) विदेश नीति निर्धारण पर विचारधारा के विशिष्ट प्रभाव का अध्ययन करना।
(C) किसी राज्य के दैनिक कार्यों के नैतिक आयामों का मूल्यांकन करना।
(D) रणनीतिक अंतःक्रियाओं का मॉडल तैयार करना जहाँ परिणाम सभी के विकल्पों पर निर्भर करते हैं।

5. अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के निर्णय-प्रक्रिया दृष्टिकोण के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए।
(A) यह समझने का प्रयास करता है कि विदेश नीति के निर्णय कैसे और क्यों लिए जाते हैं।
(B) यह अक्सर नौकरशाही राजनीति सहित राज्य की आंतरिक गतिशीलता की जांच करता है।
(C) यह सभी परिस्थितियों में राज्य को एक एकात्मक, तर्कसंगत अभिनेता के रूप में मानता है।
(D) यह निर्णय लेने वालों की धारणाओं और मनोवैज्ञानिक कारकों पर विचार करता है।

6. राज्य A, जो एक छोटा राष्ट्र है, अपनी रणनीतिक स्थिति और एक महत्वपूर्ण जलमार्ग पर अपने नियंत्रण का लाभ बड़े और अधिक शक्तिशाली राज्यों की नीतियों को प्रभावित करने के लिए उठाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में किस अवधारणा का अनुप्रयोग है?
(A) मित्र राष्ट्रों के बीच वैचारिक एकरूपता स्थापित करना।
(B) राष्ट्रीय शक्ति के एक विशिष्ट तत्व का अधिग्रहण और उपयोग करना।
(C) अंतर्राष्ट्रीय गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत का पालन करना।
(D) स्वैच्छिक निरस्त्रीकरण की औपचारिक प्रक्रिया को लागू करना।

7. अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में 'राष्ट्रीय हित' की सबसे उपयुक्त परिभाषा क्या है?
(A) किसी राष्ट्र के लोगों के सामूहिक नैतिक मूल्य और नैतिक आकांक्षाएं।
(B) एक स्थिर और अपरिवर्तनीय सिद्धांत जो हर समय विदेश नीति को निर्देशित करता है।
(C) सरकार के सत्तारूढ़ दल द्वारा प्रचारित आधिकारिक राज्य विचारधारा।
(D) वे लक्ष्य जिन्हें एक राज्य अपनी सुरक्षा और राष्ट्रीय कल्याण सुनिश्चित करने के लिए अपनाता है।

8. निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन शामिल हैं, जिन्हें अभिकथन (A) और कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है। इन दोनों कथनों का सावधानीपूर्वक परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:
अभिकथन (A): यथार्थवादी सिद्धांत का मानना है कि एक अराजक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में, राज्य अपनी सुरक्षा और शक्ति को अन्य सभी चीजों से ऊपर प्राथमिकता देते हैं।
कारण (R): नियमों को लागू करने के लिए एक केंद्रीय विश्व सरकार की अनुपस्थिति राज्यों को स्वयं-सहायता के माहौल में कार्य करने के लिए विवश करती है।
(A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।

NODIA

Q. शक्ति
R. विचारधारा
S. कूटनीति

सूची II: (परिभाषा)

1. राजनीति और समाज के बारे में विश्वासों और मूल्यों का एक सुसंगत समूह
2. दूसरों के व्यवहार को प्रभावित करने की क्षमता
3. लक्ष्य जो एक राज्य अपनी सुरक्षा और समृद्धि के लिए अपनाता है
4. राज्यों के बीच संवाद करने का अभ्यास

कूट:
(A) P-1, Q-2, R-4, S-3
(B) P-3, Q-2, R-1, S-4
(C) P-2, Q-3, R-1, S-4
(D) P-3, Q-1, R-2, S-4

75. वह अवधारणा कि राज्य सभी कानूनों के लिए सर्वोच्च सत्ता है और उसके ऊपर कोई अन्य नहीं है:
(A) हस्तक्षेप
(B) गठबंधन
(C) कूटनीति
(D) संप्रभुता

76. पारंपरिक हथियारों का उपयोग करके दो या दो से अधिक संप्रभु राज्यों के बीच लड़े गए युद्ध को कहा जाता है:
(A) एक जातीय संघर्ष
(B) एक अंतर-राज्यीय युद्ध
(C) एक जैव-रासायनिक युद्ध
(D) एक आंतरिक विवाद

77. यथार्थवादी दृष्टिकोण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन I: यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को स्वार्थी राज्यों के बीच शक्ति के संघर्ष के रूप में देखता है।
कथन II: यह राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर मानवाधिकारों और अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता को प्राथमिकता देता है।
(A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं।
(C) कथन I सत्य है, लेकिन कथन II असत्य है।
(D) कथन I असत्य है, लेकिन कथन II सत्य है।

78. अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अंतःक्रियाओं, इनपुट, आउटपुट और फीडबैक लूप के एक जटिल जाल के रूप में अध्ययन किस दृष्टिकोण की विशेषता है?
(A) व्यवस्था दृष्टिकोण
(B) आदर्शवादी दृष्टिकोण
(C) खेल सिद्धांत दृष्टिकोण
(D) निर्णय-प्रक्रिया दृष्टिकोण

79. शक्ति के अधिग्रहण में निम्नलिखित में से किसे छोड़कर सभी शामिल हो सकते हैं:
(A) एक सुदृढ़ अर्थव्यवस्था बनाना
(B) सक्रिय रूप से पूर्ण निरस्त्रीकरण और सेना को समाप्त करने का प्रयास करना
(C) सैन्य शक्ति विकसित करना
(D) रणनीतिक गठबंधन बनाना

80. अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में ' शक्ति' की अवधारणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. शक्ति एक बहुआयामी अवधारणा है, जिसमें सैन्य, आर्थिक और सांस्कृतिक पहलू शामिल हैं।
2. शक्ति संसाधनों का स्वामित्व स्वतः ही प्रभाव में परिवर्तित नहीं हो जाता है।
3. शक्ति केवल किसी राज्य के पास मौजूद परमाणु हथियारों की संख्या से परिभाषित होती है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3

81. "राष्ट्रीय हित का निर्धारण और प्रचार" में शामिल है:
(A) लक्ष्यों की पहचान करने की प्रक्रिया और फिर उन्हें प्राप्त करने के लिए कूटनीति जैसे उपकरणों का उपयोग करना।
(B) केवल राज्य के प्रमुख का पृथक रूप से कार्य करना।
(C) अन्य सभी राज्यों की शक्ति और हितों की अनदेखी करना।
(D) एक ही, अपरिवर्तनीय विचारधारा के आदेशों का सख्ती से पालन करना।

82. समकालीन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विचारधारा की प्रासंगिकता पर अक्सर बहस होती है, लेकिन इसे अभी भी देखा जा सकता है:
(A) शस्त्र नियंत्रण संधियों के विशुद्ध तकनीकी पहलुओं में।
(B) राज्य की भौगोलिक स्थिति में।
(C) सकल घरेलू उत्पाद की गणना में।
(D) मानवाधिकारों और शासन के स्वरूपों पर विवादों में।

83. युद्ध का कौन सा कारण क्षेत्र, संसाधनों या रणनीतिक लाभ को लेकर संघर्ष से संबंधित है?
(A) वैचारिक कारण
(B) जातीय कारण
(C) राजनीतिक या भू-राजनीतिक कारण
(D) व्यवस्थागत कारण

84. "परस्पर सुनिश्चित विनाश" की अवधारणा किसका एक मुख्य घटक है?
(A) परमाणु निवारण सिद्धांत
(B) आदर्शवादी दृष्टिकोण
(C) गुटनिरपेक्ष आंदोलन
(D) अंतर्राष्ट्रीय संधि कानून

Click Here to Buy book on Amazon

177. नाटो जैसे सैन्य समझौते में शामिल होने का विकल्प चुनने वाला राज्य किसमें प्रवेश कर रहा है:
(A) गुटनिरपेक्षता का कार्य
(B) निरस्त्रीकरण के लिए समझौता
(C) गठबंधन
(D) हस्तक्षेप

178. शक्ति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन I: सैन्य उपकरण जैसे शक्ति के मूर्त तत्व ही एकमात्र कारक हैं जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में परिणाम निर्धारित करते हैं।
कथन II: राष्ट्रीय मनोबल और राजनयिक कौशल जैसे अमूर्त तत्व अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की राज्य की क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं।
(A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं।
(C) कथन I सत्य है, लेकिन कथन II असत्य है।
(D) कथन I असत्य है, लेकिन कथन II सत्य है।

179. आत्मनिर्णय या स्वायत्तता के लिए किसी विशेष पहचान समूह की इच्छा से प्रेरित संघर्ष किस श्रेणी में आता है?
(A) विशुद्ध रूप से आर्थिक युद्ध।
(B) एक जातीय विवाद।
(C) वैश्विक विजय का युद्ध।
(D) एक व्यवस्थागत संक्रमण युद्ध।

180. संधि कानून में "पाक्टा संट सरवेंडा" की अवधारणा का अर्थ है:
(A) समझौतों का पालन सद्भावना से किया जाना चाहिए।
(B) संधियाँ बाध्यकारी नहीं होती हैं।
(C) परिस्थितियों में मौलिक परिवर्तन किसी संधि को अमान्य कर सकता है।
(D) केवल शक्तिशाली राष्ट्रों को ही संधियों का पालन करने की आवश्यकता है।

181. वैश्वीकरण ने किन अभिनेताओं के उदय को सुगम बनाया है जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के राज्य-केंद्रित दृष्टिकोण को चुनौती देते हैं?
(A) राष्ट्रीय विधायिकाएँ और स्थानीय सरकारें।
(B) पारंपरिक राजनयिक दल।
(C) ऐतिहासिक समाज और संग्रहालय।
(D) बहुराष्ट्रीय निगम और अंतर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठन।

182. शीतयुद्ध के अंत का एक यथार्थवादी विश्लेषण किस पर ध्यान केंद्रित करने की संभावना रखता है?
(A) लोकतांत्रिक आदर्शों की नैतिक श्रेष्ठता।
(B) सोवियत संघ के आंतरिक पतन के कारण शक्ति संतुलन में बदलाव।
(C) संघर्ष को समाप्त करने में अंतर्राष्ट्रीय कानून की सफलता।
(D) विश्वास बढ़ाने में बेहतर संचार की भूमिका।

183. कूटनीति का मुख्य लक्ष्य है:
(A) एक अपरिहार्य युद्ध के लिए तैयारी करना।
(B) एकल वैश्विक विचारधारा को बढ़ावा देना।
(C) अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रबंधित करना और हिंसा का सहारा लिए बिना संघर्षों को हल करना।
(D) बल प्रयोग के माध्यम से राज्य की इच्छा को लागू करना।

184. यह तर्क कि किसी भी राज्य को दूसरे राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होना चाहिए, किस सिद्धांत पर आधारित है?
(A) सामूहिक सुरक्षा
(B) शस्त्रों की दौड़
(C) वैश्वीकरण
(D) संप्रभु समानता

185. एक राज्य जो अपने राष्ट्रीय हित को अन्य देशों में अपनी क्रांतिकारी विचारधारा फैलाने के रूप में परिभाषित करता है, वह किसका उदाहरण है?
(A) अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विचारधारा की भूमिका और प्रासंगिकता।
(B) विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के प्रति प्रतिबद्धता।
(C) गुटनिरपेक्षता का अभ्यास।
(D) पूर्ण निरस्त्रीकरण की नीति।

186. कौन सा सिद्धांत संयुक्त राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और शांति के लिए एक मूल्यवान उपकरण के रूप में देखने की सर्वाधिक संभावना रखता है?
(A) यथार्थवाद
(B) खेल सिद्धांत
(C) आदर्शवाद
(D) व्यवस्था सिद्धांत

187. प्रतिद्वंद्वी राज्यों द्वारा सैन्य उपकरणों की मात्रा या गुणवत्ता में प्रतिस्पर्धी और अक्सर तीव्र वृद्धि को कहा जाता है:
(A) शस्त्रों की दौड़
(B) निरस्त्रीकरण
(C) शस्त्र नियंत्रण
(D) कूटनीति

188. निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन शामिल हैं, जिन्हें अभिकथन (A) और कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है। इन दोनों कथनों का सावधानीपूर्वक परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:
अभिकथन (A): शीतयुद्ध के दौरान, कई नए स्वतंत्र राष्ट्रों ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई।
कारण (R): वे संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच वैचारिक और सैन्य टकराव में सम्मिलित होने से बचना चाहते थे।
(A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सत्य है लेकिन R असत्य है।

NODIA

(A) सैन्य विजय के माध्यम से शक्ति का अधिग्रहण।
(B) औपचारिक संधि अनुसमर्थन की प्रक्रिया।
(C) परमाणु निवारण की रणनीति।
(D) मृदु शक्ति के माध्यम से राष्ट्रीय हित का प्रचार।

98. निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन शामिल हैं, जिन्हें अभिकथन (A) और कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है। इन दोनों कथनों का सावधानीपूर्वक परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:
अभिकथन (A): निर्णय-प्रक्रिया दृष्टिकोण राज्य को एक एकात्मक अभिनेता मानने की यथार्थवादी धारणा की आलोचना करता है।
कारण (R): यह रेखांकित करता है कि विदेश नीति के निर्णय अक्सर राज्य तंत्र के भीतर विभिन्न व्यक्तियों और समूहों के बीच जटिल अंतःक्रियाओं, संघर्षों और समझौतों का उत्पाद होते हैं।
(A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(D) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

99. इनमें से कौन किसी राज्य की शक्ति के प्रयोग पर एक सीमा है?
(A) इसकी अपनी सैन्य शक्ति
(B) अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानदंड
(C) इसके आर्थिक संसाधन
(D) इसका परिभाषित राष्ट्रीय हित

100. अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के आदर्शवादी दृष्टिकोण को अक्सर क्या कहा जाता है?
(A) शक्ति की राजनीति
(B) उदारवाद या यूटोपियनवाद
(C) संरचनात्मक यथार्थवाद
(D) खेल सिद्धांत

101. खतरे की "धारणा", भले ही वह वस्तुनिष्ठ वास्तविकता पर आधारित न हो, किसी राज्य को ऐसी कार्रवाई करने के लिए प्रेरित कर सकती है जो वास्तविक संघर्ष को भड़का दे। यह किस दृष्टिकोण के महत्व को उजागर करता है?
(A) संचार दृष्टिकोण
(B) व्यवस्था दृष्टिकोण
(C) यथार्थवादी दृष्टिकोण
(D) खेल सिद्धांत

102. अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विचारधारा की भूमिका सर्वाधिक स्पष्ट तब होती है जब राज्य:
(A) तुलनात्मक लाभ के आधार पर व्यापार में संलग्न होते हैं।
(B) अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में मत्स्य पालन के अधिकारों पर वार्ता करते हैं।
(C) किसी मिशन या विश्वासों के समूह के आधार पर अपने कार्यों को उचित ठहराते हैं।
(D) मानक राजनयिक प्रोटोकॉल का पालन करते हैं।

103. युद्ध की प्राथमिक प्रकृति यह है कि यह:
(A) बिना किसी राजनीतिक उद्देश्य के एक यादृच्छिक और संवेदनहीन कार्य है।
(B) नीति का एक साधन है जिसका उपयोग राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है।
(C) एक ऐसी घटना है जो केवल पूर्व-आधुनिक समय में हुई थी।
(D) एक ऐसी घटना है जिसे संधि कानून द्वारा पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है।

104. शीतयुद्ध काल के शब्दों के संबंध में सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:
सूची I: (शब्द)
P. द्विध्रुवीयता
Q. गठबंधन
R. गुटनिरपेक्षता
S. निवारण
सूची II: (विवरण)
1. नाटो और वारसॉ पैक्ट जैसे सैन्य समझौते
2. महाशक्ति गुटों से स्वतंत्रता बनाए रखना
3. दो प्रमुख शक्तियों के इर्द-गिर्द संरचित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था
4. प्रतिशोध की धमकी के माध्यम से हमले को रोकना
कूट:
(A) P-3, Q-1, R-2, S-4
(B) P-1, Q-3, R-4, S-2
(C) P-3, Q-2, R-1, S-4
(D) P-4, Q-1, R-2, S-3

105. एक राज्य जो सैन्य गठबंधन में शामिल होने से इनकार करता है और स्वतंत्र विदेश नीति अपनाता है, वह किसका अभ्यास कर रहा है:
(A) हस्तक्षेपवाद
(B) निवारण
(C) शस्त्रों की दौड़
(D) गुटनिरपेक्षता

106. अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत राज्यों का एक प्रमुख कर्तव्य 'विवादों का शांतिपूर्ण समाधान' है। निम्नलिखित में से कौन इस कर्तव्य का उल्लंघन करेगा?
(A) सीमा विवाद को हल करने के लिए बिना उकसावे के सैन्य हमला करना।
(B) द्विपक्षीय वार्ता प्रारंभ करना।
(C) किसी तटस्थ तीसरे पक्ष से मध्यस्थता की मांग करना।
(D) विवाद को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रस्तुत करना।

Downloaded from www.pdf.tube

107. 'वैश्वीकरण' की अवधारणा किसके महत्व में कमी का संकेत देती है?
(A) राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाएं
(B) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार
(C) भौगोलिक सीमाएँ और राज्य संप्रभुता
(D) संचार प्रौद्योगिकी

108. शामिल अभिनेताओं के विकल्पों को समझने के लिए 'पे-ऑफ मैट्रिक्स' स्थापित करके संघर्ष का विश्लेषण करने में कौन सा दृष्टिकोण सर्वाधिक रुचि रखेगा?
(A) खेल सिद्धांत दृष्टिकोण
(B) आदर्शवादी दृष्टिकोण
(C) संचार दृष्टिकोण
(D) निर्णय-प्रक्रिया दृष्टिकोण

109. 'राष्ट्रीय हित' के संबंध में सही कथन की पहचान कीजिए।
(A) यह सार्वभौमिक रूप से सहमत है और सभी राज्यों के लिए समान है।
(B) यह एक स्थिर अवधारणा है जो समय के साथ नहीं बदलती है।
(C) इसका संबंध केवल सैन्य शक्ति से है।
(D) इसका निर्धारण एक राजनीतिक प्रक्रिया है जो देश के नेतृत्व से प्रभावित होती है।

110. राष्ट्रीय हित को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित उपकरणों पर विचार कीजिए:
1. कूटनीति और वार्ता
2. आर्थिक सहायता और प्रतिबंध
3. सैन्य बल और गठबंधन

अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अपने उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए राज्य द्वारा उपरोक्त में से किसका उपयोग किया जा सकता है?
(A) केवल 1
(B) केवल 1 और 3
(C) केवल 2 और 3
(D) 1, 2 और 3

111. निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः युद्ध या संघर्ष के एक अलग प्रकार के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है?
(A) दार्शनिक बहस के युद्ध
(B) जातीय विवाद
(C) परमाणु युद्ध
(D) जैव-रासायनिक युद्ध

112. यह विचार कि किसी एक राज्य या राज्यों के गठबंधन को इतना शक्तिशाली नहीं होने दिया जा सकता कि वह अन्य सभी पर हावी हो जाए, कहलाता है:
(A) हस्तक्षेप का अधिकार
(B) शीतयुद्ध का अंत
(C) शक्ति संतुलन
(D) गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत

113. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन I: शस्त्र नियंत्रण का अर्थ सदैव सभी हथियारों का पूर्ण विनाश होता है।
कथन II: निरस्त्रीकरण समझौतों के माध्यम से विशिष्ट प्रकार के हथियारों के नियमन और सीमा को संदर्भित करता है।
(A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं।
(C) कथन I सत्य है, लेकिन कथन II असत्य है।
(D) कथन I असत्य है, लेकिन कथन II सत्य है।

114. सशस्त्र संघर्ष के दौरान राज्यों के आचरण को नियंत्रित करने वाला कानूनी ढांचा किसका भाग है?
(A) अंतर्राष्ट्रीय कानून।
(B) निवारण का सिद्धांत।
(C) शस्त्रों की दौड़ की अवधारणा।
(D) गुटनिरपेक्षता की नीति।

115. शीतयुद्ध के बाद की दुनिया की एक विशिष्ट विशेषता रही है:
(A) एक स्पष्ट द्विध्रुवीय संरचना।
(B) सभी सैन्य गठबंधनों का विलुप्त होना।
(C) राष्ट्रवाद के सभी स्वरूपों का अंत।
(D) वैश्वीकरण का बढ़ता प्रभाव।

116. एक यथार्थवादी तर्क देगा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून:
(A) अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सबसे शक्तिशाली बल है।
(B) केवल तभी प्रभावी होता है जब वह शक्तिशाली राज्यों के हितों को दर्शाता है।
(C) वैश्विक सद्भाव और न्याय प्राप्त करने का एक उपकरण है।
(D) युद्ध का प्राथमिक कारण है।

117. राज्यों द्वारा अपने समझौतों को अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत कानूनी रूप से प्रवर्तनीय बनाने की प्रक्रिया किसका एक केंद्रीय भाग है?
(A) निवारण
(B) शस्त्रों की दौड़
(C) संधि कानून
(D) जातीय विवाद

118. "शक्ति का उपयोग और सीमाएँ" यह सुझाव देता है कि:
(A) शक्ति असीमित है और इसका उपयोग बिना किसी परिणाम के किया जा सकता है।
(B) अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति एक पुरानी अवधारणा है।
(C) केवल सैन्य शक्ति सीमाओं के अधीन है।
(D) यहाँ तक कि सर्वाधिक शक्तिशाली राज्यों को भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की क्षमता पर बाधाओं का सामना करना पड़ता है।

119. कौन सा दृष्टिकोण यह तर्क देने की सर्वाधिक संभावना रखता है कि "युद्ध एक त्रुटि है, जो गलतफहमी और विफल संचार का परिणाम है"?

NODIA

(A) संचार दृष्टिकोण
(B) यथार्थवादी दृष्टिकोण
(C) व्यवस्था दृष्टिकोण
(D) खेल सिद्धांत दृष्टिकोण

120. संघर्ष की प्रकृति के संबंध में गलत युग्म की पहचान कीजिए।
(A) जातीय विवाद : पहचान और संस्कृति को लेकर संघर्ष
(B) शांतिपूर्ण समाधान : सशस्त्र संघर्ष वाला संघर्ष
(C) परमाणु युद्ध : सामूहिक विनाश के हथियारों वाला संघर्ष
(D) जैव-रासायनिक युद्ध : रोगों को हथियार के रूप में प्रयोग करने वाला संघर्ष

121. शीतयुद्ध के अंत ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की नई संरचना के बारे में बहस छेड़ दी, जिसे कुछ विद्वान इस रूप में वर्णित करते हैं:
(A) द्विध्रुवीय
(B) गुटनिरपेक्ष
(C) एकध्रुवीय या बहुध्रुवीय
(D) स्थायी रूप से स्थिर

122. किसी राज्य का संविधान जो एक विशिष्ट राजनीतिक विचारधारा (जैसे समाजवाद, उदारवाद) के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की घोषणा करता है, उसकी विदेश नीति को प्रभावित कर सकता है। यह किसका उदाहरण है?
(A) अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विचारधारा की भूमिका।
(B) निरस्त्रीकरण की प्रक्रिया।
(C) संधि कानून का कार्य।
(D) परमाणु निवारण की कार्यप्रणाली।

123. अराजक विश्व में आत्मनिर्भर होने और अपने अस्तित्व को सुरक्षित रखने की राज्य की क्षमता को यथार्थवादियों द्वारा क्या कहा जाता है?
(A) परस्पर निर्भरता
(B) वैश्विक शासन
(C) गुटनिरपेक्षता
(D) स्वयं-सहायता

124. निम्नलिखित में से कौन आदर्शवादी दृष्टिकोण की एक मौलिक धारणा है?
(A) अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था युद्ध की स्थायी स्थिति में है।
(B) मानवीय तर्क और सहयोग एक अधिक शांतिपूर्ण विश्व की ओर ले जा सकते हैं।
(C) अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में केवल राज्य ही महत्वपूर्ण हैं।
(D) सैन्य शक्ति ही राष्ट्र की शक्ति का एकमात्र वास्तविक मानक है।

125. निम्नलिखित में से कौन "सुरक्षा दुविधा" को परिभाषित करता है?
(A) ऐसी स्थिति जहाँ दो राज्य पूर्ण निरस्त्रीकरण के लिए सहमत हों।
(B) ऐसी स्थिति जहाँ एक राज्य के पास बहुत अधिक सैन्य गठबंधन हों।
(C) ऐसी स्थिति जहाँ अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक राज्य द्वारा की गई कार्रवाइयों को अन्य राज्यों द्वारा खतरे के रूप में देखा जाता है, जिससे वे भी वैसी ही प्रतिक्रिया करते हैं।
(D) ऐसी स्थिति जहाँ राज्य का राष्ट्रीय हित स्पष्ट न हो।

126. कानूनी मानदंडों और सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से "युद्ध की रोकथाम और उन्मूलन" किसका एक केंद्रीय विषय है:
(A) शक्ति की राजनीति का यथार्थवादी सिद्धांत।
(B) शस्त्रों की दौड़ की अवधारणा।
(C) बलपूर्वक हस्तक्षेप का अभ्यास।
(D) आदर्शवादी विचार और अंतर्राष्ट्रीय कानून।

127. यदि किसी देश का विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और गुप्तचर सेवाएँ इस बात पर असहमत हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संकट पर कैसी प्रतिक्रिया दी जाए, तो यह किस सैद्धांतिक दृष्टिकोण के मूल सिद्धांत को उजागर करता है?
(A) निर्णय-प्रक्रिया दृष्टिकोण
(B) व्यवस्था सिद्धांत
(C) आदर्शवाद
(D) यथार्थवाद

128. निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन शामिल हैं, जिन्हें अभिकथन (A) और कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है। इन दोनों कथनों का सावधानीपूर्वक परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:
अभिकथन (A): शीतयुद्ध प्रतिद्वंद्वी सैन्य गठबंधनों के गठन की विशेषता थी।
कारण (R): द्विध्रुवीय व्यवस्था में, राज्य अक्सर दो महाशक्तियों में से एक के साथ जुड़कर अपनी शक्ति और सुरक्षा बढ़ाने का प्रयास करते हैं।
(A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(D) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

129. 'कूटनीति' शब्द में निम्नलिखित में से किसे छोड़कर सभी गतिविधियाँ शामिल हैं:
(A) संधियों की शांतिपूर्ण वार्ता।
(B) विदेश में राज्य के हितों का प्रतिनिधित्व।
(C) युद्ध की एकपक्षीय घोषणा।
(D) विदेशों के बारे में सूचना एकत्र करना।

130. आकार या शक्ति की परवाह किए बिना सभी राज्यों की कानूनी समानता किसका आधारभूत सिद्धांत है?
(A) अंतर्राष्ट्रीय कानून
(B) यथार्थवादी दृष्टिकोण
(C) व्यवस्था दृष्टिकोण
(D) निवारण सिद्धांत

Click Here to Buy book on Amazon

154. कौन सा सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना, विशेष रूप से शक्ति के वितरण को राज्य के व्यवहार के प्राथमिक निर्धारक के रूप में देखता है?
(A) निर्णय-प्रक्रिया सिद्धांत
(B) संचार सिद्धांत
(C) व्यवस्था सिद्धांत
(D) आदर्शवाद

155. गठबंधनों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन I: गठबंधन सदैव स्थायी होते हैं और उन्हें कभी तोड़ा नहीं जा सकता।
कथन II: गठबंधन शक्ति संतुलन की राजनीति की एक प्रमुख विशेषता है, जहाँ राज्य एक सामान्य खतरे का सामना करने के लिए एक साथ जुड़ते हैं।
(A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं।
(C) कथन I सत्य है, लेकिन कथन II असत्य है।
(D) कथन I असत्य है, लेकिन कथन II सत्य है।

156. अत्यधिक बल प्रयोग की धमकी के माध्यम से युद्ध की रोकथाम किसका केंद्रीय तर्क है?
(A) निरस्त्रीकरण
(B) निवारण
(C) कूटनीति
(D) गुटनिरपेक्षता

157. गैर-हस्तक्षेप का सिद्धांत किस सिद्धांत का प्रत्यक्ष परिणाम है?
(A) वैश्वीकरण
(B) निवारण
(C) गठबंधन
(D) संप्रभुता

158. निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन शामिल हैं, जिन्हें अभिकथन (A) और कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है। इन दोनों कथनों का सावधानीपूर्वक परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:
अभिकथन (A): राष्ट्रीय हित को बढ़ावा देना किसी भी राज्य की विदेश नीति का प्राथमिक लक्ष्य है।
कारण (R): राष्ट्रीय हित लक्ष्यों की एक वस्तुनिष्ठ रूप से परिभाषित और सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत सूची है जिसे सभी राज्य समान रूप से अपनाते हैं।
(A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(D) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

159. वह युद्ध जो परमाणु विखंडन या संलयन के उपयोग की विशेषता रखता है, वह है:
(A) जैव-रासायनिक युद्ध
(B) पारंपरिक युद्ध
(C) परमाणु युद्ध
(D) जातीय विवाद

160. अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का कौन सा सैद्धांतिक दृष्टिकोण शांति को बढ़ावा देने में साझा मानदंडों, मूल्यों और लोकतांत्रिक संस्थानों के महत्व पर बल देने की सर्वाधिक संभावना रखता है?
(A) आदर्शवादी
(B) यथार्थवादी
(C) व्यवस्था
(D) खेल सिद्धांत

161. वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी राज्य का नेतृत्व विश्व में अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को परिभाषित करता है, उसे कहा जाता है:
(A) निरस्त्रीकरण की प्रक्रिया।
(B) हस्तक्षेप का अभ्यास।
(C) शस्त्रों की दौड़ की गतिशीलता।
(D) राष्ट्रीय हित का निर्धारण।

162. राज्य पर वैश्वीकरण का एक प्रमुख प्रभाव क्या रहा है?
(A) सभी क्षेत्रों में राज्य की शक्ति का पूर्ण क्षरण।
(B) वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक मानदंडों के अनुरूप होने के लिए राज्यों पर बढ़ता दबाव।
(C) अलगाववादी नीतियों की ओर सार्वभौमिक वापसी।
(D) राष्ट्रीय पहचान का पूर्ण उन्मूलन।

163. व्यक्तिगत नेताओं के व्यक्तित्व, विश्वास प्रणाली और संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं विदेश नीति को कैसे प्रभावित करती हैं, इसका अध्ययन किसका एक प्रमुख भाग है?
(A) व्यवस्था दृष्टिकोण
(B) यथार्थवादी दृष्टिकोण
(C) निर्णय-प्रक्रिया दृष्टिकोण
(D) खेल सिद्धांत दृष्टिकोण

164. अंतर्राष्ट्रीय कानून की अवधारणाओं के संबंध में सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:
सूची I: (अवधारणा)
P. संप्रभुता
Q. हस्तक्षेप
R. संधि
S. शांतिपूर्ण समाधान
सूची II: (अर्थ)
1. दूसरे राज्य के मामलों में बलपूर्वक हस्तक्षेप
2. राज्यों के बीच एक औपचारिक समझौता
3. बल का सहारा लिए बिना विवादों को सुलझाना
4. अपने क्षेत्र के भीतर राज्य का सर्वोच्च प्राधिकार
कूट:
(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-4, Q-1, R-2, S-3

NODIA

(B) मुख्य रूप से अपनी विचारधारा में साम्यवादी थे।
(C) जिन्होंने एक शक्तिशाली तीसरा सैन्य गठबंधन बनाया था।
(D) जिनके पास परमाणु हथियारों का एक समूह था।

142. राज्यों के बीच लिखित रूप में संपन्न और अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा शासित एक औपचारिक, बाध्यकारी समझौता है:
(A) युद्ध की घोषणा
(B) राजनयिक विरोध
(C) राष्ट्रीय हित का वक्तव्य
(D) संधि

143. सरकार और एक विद्रोही समूह के बीच राज्य की सीमाओं के भीतर मुख्य रूप से लड़ा जाने वाला युद्ध किस प्रकार का है:
(A) अंतर-राज्यीय संघर्ष
(B) अंतः-राज्यीय या गृहयुद्ध
(C) परमाणु युद्ध
(D) व्यवस्थागत युद्ध

144. निम्नलिखित में से कौन 'शस्त्र नियंत्रण' का सबसे अच्छा उदाहरण है?
(A) किसी देश की सेना के आकार को दोगुना करने का एकपक्षीय निर्णय।
(B) दुनिया भर में सभी सेनाओं का पूर्ण उन्मूलन।
(C) एक संधि जो वायुमंडल में परमाणु हथियारों के परीक्षण पर प्रतिबंध लगाती है।
(D) एक नए, अधिक शक्तिशाली प्रकार के बम का विकास।

145. यथार्थवाद के विपरीत, आदर्शवादी दृष्टिकोण किसमें गहरा विश्वास रखता है?
(A) मानवीय प्रगति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की संभावना।
(B) संघर्ष की अपरिहार्यता।
(C) शक्ति संतुलन।
(D) अन्य सभी अभिनेताओं पर राज्य की प्रधानता।

146. एक विद्वान जो विश्लेषण करता है कि कैसे नेताओं के बीच गलत धारणाओं और संज्ञानात्मक पूर्वाग्रहों के कारण युद्ध प्रारंभ हुआ, वह किसके ढांचे के भीतर कार्य कर रहा है:
(A) व्यवस्था दृष्टिकोण
(B) संचार और निर्णय-प्रक्रिया दृष्टिकोण
(C) यथार्थवादी दृष्टिकोण
(D) खेल सिद्धांत

147. राज्य की शक्ति के उपयोग पर एक सीमा हो सकती है:
(A) इसकी अपनी बड़ी जनसंख्या।
(B) इसके विशाल प्राकृतिक संसाधन।
(C) इसका उन्नत तकनीकी आधार।
(D) विदेशी हस्तक्षेप का विरोध करने वाला घरेलू जनमत।

148. "शीतयुद्ध के अंत" को अक्सर किसके द्वारा प्रतीकित किया जाता है?
(A) बर्लिन की दीवार का गिरना।
(B) वारसॉ पैक्ट का गठन।
(C) क्यूबा मिसाइल संकट।
(D) कोरियाई युद्ध का प्रारंभ।

149. अंतर्राष्ट्रीय कानून के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए।
(A) यह राज्यों के बीच संबंधों के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है।
(B) इसके स्रोतों में संधियाँ, रीति-रिवाज और कानून के सामान्य सिद्धांत शामिल हैं।
(C) यह प्रवर्तन के लिए एक केंद्रीकृत विश्व पुलिस बल पर भारी निर्भर करता है।
(D) यह संप्रभु राज्यों के अधिकारों और कर्तव्यों को संबोधित करता है।

150. अंतर्राष्ट्रीय संधि के विशिष्ट जीवन चक्र के निम्नलिखित चरणों को सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए:
1. प्रवर्तन
2. वार्ता और प्रारूपण
3. राज्यों द्वारा अनुसमर्थन
4. हस्ताक्षर
(A) 2, 4, 3, 1
(B) 1, 2, 4, 3
(C) 4, 2, 1, 3
(D) 2, 3, 4, 1

151. अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में "विचारधारा" संघर्ष का स्रोत हो सकती है जब:
(A) दो राज्य एक ही विचारधारा साझा करते हैं।
(B) प्रतिस्पर्धी और प्रचारक विचारधारा वाले दो राज्य एक-दूसरे को खतरे के रूप में देखते हैं।
(C) विचारधारा विदेश नीति से पूर्णतः पृथक हो जाती है।
(D) राज्य वैचारिक शुद्धता के स्थान पर व्यावहारिक हितों को प्राथमिकता देते हैं।

152. विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की कौन सी पद्धति पक्षों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी है?
(A) न्यायिक समाधान या अधिनिर्णय
(B) सद्भावना सेवा
(C) मध्यस्थता
(D) वार्ता

153. अपनी संस्कृति, राजनीतिक आदर्शों और नीतियों के आकर्षण से प्राप्त राज्य की शक्ति को क्या कहा जाता है:
(A) कठोर शक्ति
(B) सैन्य शक्ति
(C) आर्थिक शक्ति
(D) मृदु शक्ति

NODIA

85. निम्नलिखित में से कौन संधि कानून का एक प्रमुख घटक है?
(A) हस्तक्षेप करने का एकपक्षीय अधिकार
(B) शस्त्रों की दौड़ की अवधारणा
(C) गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत
(D) अनुसमर्थन और प्रवर्तन की प्रक्रिया

86. अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत राज्य का प्रमुख कर्तव्य क्या है?
(A) हर कीमत पर अपने क्षेत्र का विस्तार करना।
(B) अपने अंतर्राष्ट्रीय कानूनी दायित्वों का पालन करना।
(C) सैन्य गठबंधन बनाना।
(D) एकल वैश्विक संस्कृति को बढ़ावा देना।

87. "शीतयुद्ध के अंत" की एक प्रमुख विशेषता थी:
(A) वारसॉ पैक्ट का सुदृढ़ीकरण और विस्तार।
(B) जर्मनी का दो अलग-अलग राज्यों में विभाजन।
(C) पूर्वी यूरोप में साम्यवादी शासन का पतन और सोवियत संघ का विघटन।
(D) अलगाववाद की ओर वैश्विक कदम और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की अस्वीकृति।

88. यदि व्यापार विवाद में दो देश एक स्वतंत्र न्यायिक निकाय को बाध्यकारी निर्णय लेने देने के लिए सहमत होते हैं, तो वे शांतिपूर्ण समाधान की किस पद्धति का उपयोग कर रहे हैं?
(A) राजनयिक वार्ता
(B) मध्यस्थता
(C) सद्भावना सेवा
(D) अधिनिर्णय

89. एक विद्वान जो ज्ञापनों के प्रवाह, विदेश मंत्रालय बनाम रक्षा मंत्रालय के प्रभाव और प्रधानमंत्री के व्यक्तिगत विश्वासों की जांच करके विदेश नीति संकट का विश्लेषण कर रहा है, वह किस दृष्टिकोण का उपयोग कर रहा है?
(A) निर्णय-प्रक्रिया दृष्टिकोण
(B) व्यवस्था दृष्टिकोण
(C) यथार्थवादी दृष्टिकोण
(D) आदर्शवादी दृष्टिकोण

90. निम्नलिखित ऐतिहासिक चरणों को उनके सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए:
1. शीतयुद्ध के द्विध्रुवीय टकराव का चरमोत्कर्ष।
2. गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उदय।
3. शीतयुद्ध के बाद वैश्वीकरण का युग।
4. प्रथम विश्व युद्ध के बाद आदर्शवादी सिद्धांतों का निर्धारण।

(A) 4, 1, 2, 3
(B) 1, 2, 4, 3
(C) 4, 2, 1, 3
(D) 2, 4, 1, 3

91. अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का कौन सा सिद्धांत गठबंधनों को साझा शत्रु के विरुद्ध साझा हितों पर आधारित अल्पकालिक समझौते के रूप में देखेगा?
(A) आदर्शवाद
(B) संचार सिद्धांत
(C) यथार्थवाद
(D) निर्णय-प्रक्रिया सिद्धांत

92. यह तर्क कि राज्य तर्कसंगत अभिनेता हैं, जो अपने लाभ को अधिकतम करना चाहते हैं, किसका केंद्र है:
(A) खेल सिद्धांत
(B) संचार सिद्धांत
(C) आदर्शवादी दृष्टिकोण
(D) जातीय विवादों का अध्ययन

93. वैश्वीकरण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन I: यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो केवल अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के आर्थिक क्षेत्र को प्रभावित करती है।
कथन II: इसने विश्व मंच पर प्रभावशाली खिलाड़ियों के रूप में बहुराष्ट्रीय निगमों और गैर-सरकारी संगठनों जैसे गैर-राज्य अभिनेताओं के उदय को जन्म दिया है।
(A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं।
(C) कथन I सत्य है, लेकिन कथन II असत्य है।
(D) कथन I असत्य है, लेकिन कथन II सत्य है।

94. एकल राज्य की सीमाओं के भीतर विभिन्न पहचान समूहों के बीच सशस्त्र संघर्ष को किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है:
(A) एक अंतर-राज्यीय युद्ध
(B) एक परमाणु युद्ध
(C) एक व्यवस्थागत युद्ध
(D) एक जातीय संघर्ष या गृहयुद्ध

95. सभी राज्यों से हथियारों की एक विशिष्ट श्रेणी का पूर्ण उन्मूलन किसका लक्ष्य है:
(A) शस्त्र नियंत्रण
(B) निरस्त्रीकरण
(C) निवारण
(D) शस्त्रों की दौड़

96. "अन्य राज्यों को छोड़कर, अपने क्षेत्र, जनसंख्या और संसाधनों पर अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने का राज्य का अधिकार" किसकी परिभाषा है:
(A) हस्तक्षेप
(B) गठबंधन
(C) संप्रभुता
(D) विचारधारा

97. किसी देश के मूल्यों को बढ़ावा देने और विदेश नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रचार, सार्वजनिक कूटनीति और सांस्कृतिक निर्यात का उपयोग करना किसका अभ्यास है:

Downloaded from www.pdf.tube

(C) P-4, Q-2, R-1, S-3
(D) P-1, Q-4, R-3, S-2

165. शीतयुद्ध को 'शीत' कहा जाता है क्योंकि:
(A) यह आर्कटिक क्षेत्रों में लड़ा गया था।
(B) दोनों महाशक्तियों के बीच कोई प्रत्यक्ष बड़े पैमाने पर युद्ध नहीं हुआ था।
(C) यह किसी भी भावुकता या विचारधारा से रहित संघर्ष था।
(D) यह बिना किसी स्पष्ट विजेता के समाप्त हो गया।

166. निम्नलिखित में से कौन विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की विधि नहीं है?
(A) वार्ता
(B) मध्यस्थता
(C) अधिनिर्णय
(D) शस्त्रों की दौड़

167. एक आदर्शवादी तर्क देगा कि युद्ध की रोकथाम और उन्मूलन सर्वाधिक उपयुक्त रूप से किसके माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है?
(A) वैश्विक शक्ति संतुलन।
(B) एकपक्षीय सैन्य निर्माण।
(C) लोकतंत्र का प्रसार और अंतर्राष्ट्रीय कानून का सुदृढ़ीकरण।
(D) सख्त गुटनिरपेक्षता की नीति।

168. शक्ति का अधिग्रहण उन तरीकों को संदर्भित करता है जिनसे एक राज्य:
(A) अपनी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को कम कर सकता है।
(B) स्वयं को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पृथक कर सकता है।
(C) अपने राष्ट्रीय हितों को त्याग सकता है।
(D) दूसरों को प्रभावित करने की अपनी क्षमता बढ़ा सकता है।

169. शक्ति की सीमाओं के संबंध में सही कथन की पहचान कीजिए।
(A) शक्ति का उपयोग करने की लागत, भौतिक और प्रतिष्ठा दोनों के संदर्भ में, एक महत्वपूर्ण सीमा हो सकती है।
(B) अपार शक्ति वाले राज्य को किसी सीमा का सामना नहीं करना पड़ता है।
(C) अंतर्राष्ट्रीय कानून शक्ति पर एकमात्र सीमा है।
(D) शक्ति की सीमाएँ केवल छोटे राज्यों पर लागू होती हैं।

170. अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए:
1. यथार्थवादी और आदर्शवादी दृष्टिकोण
2. व्यवस्था और खेल सिद्धांत दृष्टिकोण
3. संचार और निर्णय-प्रक्रिया दृष्टिकोण
अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के लिए उपरोक्त में से कौन प्रमुख प्रतिस्पर्धी दृष्टिकोणों के रूप में पहचाने जाते हैं?
(A) केवल 1
(B) केवल 1 और 2
(C) केवल 3
(D) 1, 2 और 3

171. एक सशस्त्र हमले को उचित ठहराने के लिए दूसरे राज्य में दमित अल्पसंख्यक की ओर से कार्य करने का राज्य का दावा किसका उदाहरण है?
(A) विवाद का शांतिपूर्ण समाधान।
(B) निरस्त्रीकरण की प्रक्रिया।
(C) गुटनिरपेक्षता के प्रति प्रतिबद्धता।
(D) हस्तक्षेप का उपयोग, जो अक्सर जातीय विवादों से जुड़ा होता है।

172. अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में खेल सिद्धांत की केंद्रीय धारणा यह है कि राज्य:
(A) तर्कहीन और अप्रत्याशित हैं।
(B) तर्कसंगत अभिनेता हैं जो अपने विकल्पों की लागत और लाभों की गणना करते हैं।
(C) परोपकारी और आत्म-बलिदानी हैं।
(D) मुख्य रूप से ऐतिहासिक शिकायतों से प्रेरित हैं।

173. शीतयुद्ध के अंत ने एक 'एकध्रुवीय क्षण' उत्पन्न किया जिसका अर्थ है:
(A) विश्व का दो समान ध्रुवों में विभाजन।
(B) वैश्विक नेतृत्व में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उदय।
(C) एकमात्र प्रमुख शक्ति, संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रभुत्व।
(D) सभी परमाणु हथियारों का उन्मूलन।

174. निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है?
(A) यथार्थवाद : राज्य-केंद्रित
(B) आदर्शवाद : मानव प्रकृति का आशावादी दृष्टिकोण
(C) व्यवस्था सिद्धांत : अंतर्राष्ट्रीय संरचना पर ध्यान
(D) निर्णय-प्रक्रिया सिद्धांत : राज्य एक अखंड, एकात्मक अभिनेता के रूप में

175. अस्तित्व में रहने और आत्मरक्षा करने का राज्य का मौलिक अधिकार अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत किस कर्तव्य से आंतरिक रूप से जुड़ा हुआ है?
(A) अन्य राज्यों के विरुद्ध आक्रामकता से बचने का कर्तव्य।
(B) अन्य राज्यों में हस्तक्षेप करने का कर्तव्य।
(C) गठबंधन बनाने का कर्तव्य।
(D) शस्त्रों की दौड़ जारी रखने का कर्तव्य।

176. प्रचार जो शत्रु जनसंख्या का अमानवीयकरण करता है, जिससे युद्ध को उचित ठहराना सरल हो जाता है, संघर्ष में किसकी भूमिका को उजागर करता है?
(A) कूटनीति
(B) विचारधारा और संचार
(C) शांतिपूर्ण समाधान
(D) संधि कानून

NODIA

131. खेल सिद्धांत में, "कैदी की दुविधा" परिदृश्य दर्शाता है:
(A) क्यों राज्य एक महत्वपूर्ण पारस्परिक लाभ प्राप्त करने के लिए सदैव सहयोग करते हैं।
(B) सफल वैश्विक निरस्त्रीकरण प्राप्त करने की राजनयिक प्रक्रिया।
(C) तर्कसंगत निर्णय लेने में व्यक्तिगत विचारधारा का भारी महत्व।
(D) कैसे तर्कसंगत निर्णय सामूहिक रूप से उप-इष्टतम परिणाम की ओर ले जा सकते हैं।

132. अंतर्राष्ट्रीय कानून में राज्य का प्राथमिक कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या है?
(A) हर कीमत पर अपनी सैन्य शक्ति को अधिकतम करना।
(B) अन्य राज्यों के विरुद्ध बल प्रयोग या उसकी धमकी से बचना।
(C) सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियों को अस्वीकार करना।
(D) निर्बल राज्यों के मामलों में हस्तक्षेप करना।

133. युद्ध के कारणों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन I: संसाधनों और क्षेत्र को लेकर मूर्त विवादों से युद्ध उत्पन्न हो सकते हैं।
कथन II: युद्ध प्रतिद्वंद्वी विचारधाराओं या जातीय वैमनस्य जैसे अमूर्त कारकों के कारण भी हो सकते हैं।
(A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं।
(C) कथन I सत्य है, लेकिन कथन II असत्य है।
(D) कथन I असत्य है, लेकिन कथन II सत्य है।

134. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:
सूची I: (शब्द)
P. वैश्वीकरण
Q. शीतयुद्ध
R. गुटनिरपेक्षता
S. निरस्त्रीकरण
सूची II: (परिभाषिक विशेषता)
1. द्विध्रुवीय वैचारिक संघर्ष
2. बढ़ी हुई वैश्विक परस्पर संबद्धता
3. शस्त्रों की कमी या उन्मूलन
4. शक्ति गुटों से स्वतंत्रता की नीति
कूट:
(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-2, Q-1, R-4, S-3
(C) P-3, Q-4, R-1, S-2
(D) P-2, Q-3, R-4, S-1

135. मानवीय आधार पर 'हस्तक्षेप' की अवधारणा किस पारंपरिक सिद्धांत को चुनौती देती है?
(A) गठबंधन निर्माण
(B) शस्त्रों की दौड़
(C) राज्य की संप्रभुता और गैर-हस्तक्षेप
(D) परमाणु निवारण

136. किसी राज्य का राष्ट्रीय नेतृत्व, उसकी प्रशासनिक दक्षता और उसकी जनसंख्या का मनोबल, ये सभी माने जाते हैं:
(A) शक्ति के मूर्त तत्व
(B) राष्ट्रीय शक्ति के लिए अप्रासंगिक
(C) केवल वैश्वीकरण के उत्पाद
(D) शक्ति के अमूर्त तत्व

137. कौन सा सैद्धांतिक दृष्टिकोण किसी राज्य की विदेश नीति की व्याख्या वैश्विक संरचना के भीतर उसकी स्थिति को देखकर करेगा?
(A) व्यवस्था दृष्टिकोण
(B) आदर्शवादी दृष्टिकोण
(C) निर्णय-प्रक्रिया दृष्टिकोण
(D) संचार दृष्टिकोण

138. यह विचार कि एक विशाल परमाणु शस्त्रागार युद्ध को रोकता है क्योंकि किसी भी हमलावर को विनाश का सामना करना पड़ेगा, किसका तर्क है?
(A) शस्त्र नियंत्रण
(B) निवारण
(C) निरस्त्रीकरण
(D) कूटनीति

139. किसी राज्य के "राष्ट्रीय हित का निर्धारण और प्रचार" सर्वाधिक सटीक रूप से एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में वर्णित है जो:
(A) पूर्णतः आंतरिक है, जिसका बाहरी वातावरण से कोई संबंध नहीं है।
(B) पूर्णतः बाहरी है, जो केवल अन्य देशों के कार्यों द्वारा निर्देशित होती है।
(C) घरेलू कारकों और बाहरी अंतर्राष्ट्रीय वातावरण के बीच एक गतिशील अंतःक्रिया है।
(D) एक निश्चित वैचारिक पाठ को लागू करने का एक सरल मामला है।

140. यथार्थवादी सिद्धांत के केंद्रीय सिद्धांतों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राज्य मुख्य अभिनेता है।
2. अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था अराजक है।
3. राज्य मुख्य रूप से शक्ति और सुरक्षा की खोज से प्रेरित होते हैं।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3

141. गुटनिरपेक्ष आंदोलन उन राज्यों का एक समूह था जो:
(A) शीतयुद्ध के दौरान तटस्थ रहना चाहते थे।

Click Here to Buy book on Amazon

(D) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

189. दूसरे राज्य के व्यवहार को प्रभावित करने के लिए आर्थिक सहायता या प्रतिबंधों का उपयोग करने की राज्य की क्षमता उसकी किसका एक तत्व है:
(A) विचारधारा
(B) गुटनिरपेक्षता नीति
(C) निरस्त्रीकरण रणनीति
(D) शक्ति

190. परमाणु युद्ध और पारंपरिक युद्ध के बीच प्राथमिक अंतर क्या है?
(A) वह स्थान जहाँ यह लड़ा जाता है।
(B) प्रयुक्त हथियारों का प्रकार और संभावित विनाश का पैमाना।
(C) लड़ाकों की विचारधारा।
(D) संघर्ष की अवधि।

191. संयुक्त राष्ट्र चार्टर और प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत राज्य का एक प्रमुख कर्तव्य अंतर्राष्ट्रीय विवादों को किसके माध्यम से निपटाना है:
(A) बलपूर्वक हस्तक्षेप
(B) गठबंधन बनाना
(C) शांतिपूर्ण साधन
(D) वैचारिक वर्चस्व घोषित करना

192. सैन्य शक्ति के उपयोग पर निम्नलिखित में से कौन सी एक सीमा है?
(A) एक बड़ी सेना का होना।
(B) उन्नत तकनीक का अधिकार।
(C) राष्ट्रीय हित की स्पष्टता।
(D) उच्च हताहतों और आर्थिक लागत की संभावना।

193. यह अवधारणा कि विश्व के एक भाग की घटनाओं का विश्व के अन्य भागों पर तीव्र और महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है, किस विचार का केंद्र है?
(A) वैश्वीकरण
(B) गुटनिरपेक्षता
(C) शीतयुद्ध
(D) निवारण

194. अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांतों के संबंध में सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:
सूची I: (सिद्धांत)
P. यथार्थवाद
Q. आदर्शवाद
R. निर्णय-प्रक्रिया
S. व्यवस्था सिद्धांत
सूची II: (प्राथमिक फोकस)
1. राज्य एक गैर-एकात्मक अभिनेता के रूप में; नौकरशाही और मनोवैज्ञानिक कारक
2. अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना; ध्रुवीयता
3. शक्ति और सुरक्षा के संघर्ष में राज्य एक एकात्मक अभिनेता के रूप में
4. अंतर्राष्ट्रीय कानून, संगठन और नैतिकता
कूट:
(A) P-3, Q-4, R-1, S-2
(B) P-1, Q-2, R-3, S-4
(C) P-3, Q-1, R-4, S-2
(D) P-2, Q-4, R-1, S-3

195. दो देशों के बीच तैनात अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों की संख्या को सीमित करने का समझौता किसका एक उदाहरण है:
(A) शस्त्रों की दौड़
(B) निरस्त्रीकरण
(C) शस्त्र नियंत्रण
(D) हस्तक्षेप

196. यह धारणा कि "युद्ध अन्य साधनों से राजनीति का विस्तार है" किस परिप्रेक्ष्य के साथ सबसे निकटता से जुड़ी हुई है?
(A) आदर्शवादी, जो युद्ध को समाप्त करना चाहता है।
(B) यथार्थवादी, जो युद्ध को राज्य के एक उपकरण के रूप में देखता है।
(C) संचार, जो युद्ध को एक गलतफहमी के रूप में देखता है।
(D) खेल सिद्धांत, जो युद्ध को एक उप-इष्टतम परिणाम के रूप में देखता है।

197. वह औपचारिक प्रक्रिया जिसके द्वारा एक राज्य संधि से बाध्य होने की अपनी सहमति व्यक्त करता है, कहलाती है:
(A) हस्तक्षेप
(B) वार्ता
(C) उद्घोषणा
(D) अनुसमर्थन

198. राष्ट्रवाद का उदय संघर्ष का कारण बन सकता है जब वह आक्रामक और विस्तारवादी हो जाता है, यह घटना अक्सर किसके द्वारा प्रेरित होती है:
(A) विचारधारा
(B) निरस्त्रीकरण
(C) कूटनीति
(D) गुटनिरपेक्षता

199. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन I: राष्ट्रीय हित की अवधारणा गतिशील है और नए खतरों और अवसरों के आधार पर परिवर्तित हो सकती है।
कथन II: राष्ट्रीय हित को बढ़ावा देना केवल सैन्य माध्यमों से ही प्राप्त किया जाता है।
(A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं।
(C) कथन I सत्य है, लेकिन कथन II असत्य है।

NODIA

247. शीतयुद्ध मौलिक रूप से दो प्रतिद्वंद्वी किसके बीच एक मुकाबला था:
(A) जातीय समूह
(B) पर्यावरण नीतियां
(C) विचारधाराएँ
(D) गुटनिरपेक्षता के स्वरुप

248. निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन शामिल हैं, जिन्हें अभिकथन (A) और कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है। इन दोनों कथनों का सावधानीपूर्वक परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:
अभिकथन (A): अंतर्राष्ट्रीय कानून में वैश्विक पुलिस बल की तरह एक केंद्रीय प्रवर्तन तंत्र का अभाव है।
कारण (R): अंतर्राष्ट्रीय कानून में प्रवर्तन अक्सर स्वयं राज्यों द्वारा स्व-हित, पारस्परिकता और जवाबी उपायों पर निर्भर करता है।
(A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(D) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

249. किसी राज्य का सैन्य-औद्योगिक परिसर, उसका तकनीकी नवाचार का स्तर और उसका आर्थिक उत्पादन, ये सभी किसके लिए प्रासंगिक मूर्त तत्व हैं:
(A) शक्ति का अधिग्रहण
(B) गुटनिरपेक्षता की नीति
(C) निरस्त्रीकरण की प्रक्रिया
(D) राष्ट्रीय हित का परित्याग

250. टैंकों, विमानों और पैदल सेना का उपयोग करके दो राज्यों के बीच लड़ा जाने वाला युद्ध, लेकिन सामूहिक विनाश के हथियारों के बिना, वह है:
(A) परमाणु युद्ध
(B) जैव-रासायनिक युद्ध
(C) पारंपरिक युद्ध
(D) साइबर युद्ध

251. "इतिहास का अंत" विषय, जिसने शीतयुद्ध के बाद पश्चिमी उदारवादी लोकतंत्र की सार्वभौमिक विजय का दावा किया था, एक विशेष किसकी बोधित विजय के बारे में एक शक्तिशाली वक्तव्य था:
(A) सैन्य गठबंधन
(B) जातीय समूह
(C) केवल आर्थिक मॉडल
(D) विचारधारा

252. एक विद्वान जो परमाणु गतिरोध में दो राज्यों के विकल्पों को "चिकन के खेल" के रूप में मॉडल करता है, वह किस दृष्टिकोण का उपयोग कर रहा है?
(A) आदर्शवादी
(B) खेल सिद्धांत
(C) व्यवस्था
(D) संचार

253. पारंपरिक अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का कर्तव्य नहीं है?
(A) संधि दायित्वों का पालन करना।
(B) अन्य राज्यों की संप्रभुता का सम्मान करना।
(C) अपनी सीमाओं का अधिकतम संभव सीमा तक विस्तार करना।
(D) शांतिपूर्ण माध्यमों से विवादों को सुलझाना।

254. सूची I में दी गई अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की विचारधारा को सूची II में "युद्ध की रोकथाम" पर उसके दृष्टिकोण के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:
सूची I: (विचारधारा)
P. यथार्थवाद
Q. आदर्शवादी
R. संचार सिद्धांत
S. खेल सिद्धांत
सूची II: (युद्ध की रोकथाम पर दृष्टिकोण)
1. सहयोग के पक्ष में लाभ संरचनाओं को बदलकर रोका गया
2. संकेतों को स्पष्ट करके और गलत धारणा से बचकर रोका गया
3. अंतर्राष्ट्रीय संस्थान बनाकर और कानून को बढ़ावा देकर रोका गया
4. शक्ति संतुलन और निवारण के माध्यम से रोका गया
कूट:
(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-4, Q-3, R-1, S-2
(C) P-4, Q-3, R-2, S-1
(D) P-3, Q-4, R-2, S-1

255. सीमा पार व्यापार में तीव्र वृद्धि और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं का उदय किसकी प्रमुख विशेषताएं हैं:
(A) आर्थिक वैश्वीकरण
(B) निवारण
(C) गुटनिरपेक्षता
(D) हस्तक्षेप

256. दो अन्य प्रमुख शक्तियों के बीच संघर्ष में तटस्थ रहने और पक्ष न लेने का राज्य का निर्णय किसका एक उदाहरण है:
(A) एक गठबंधन
(B) गुटनिरपेक्षता
(C) एक हस्तक्षेप
(D) शस्त्रों की दौड़

257. 'हस्तक्षेप' और 'कूटनीति' के बीच मौलिक अंतर क्या है?
(A) हस्तक्षेप पूर्णतः शांतिपूर्ण है, जबकि कूटनीति अक्सर

Downloaded from www.pdf.tube

(C) अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था अराजक है।
(D) मानव प्रकृति अंतर्निहित रूप से अच्छी है।

212. व्यापार, निवेश और पूंजी प्रवाह के माध्यम से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं का बढ़ता एकीकरण किसका एक प्रमुख आयाम है:
(A) वैश्वीकरण
(B) शीतयुद्ध
(C) गुटनिरपेक्षता
(D) निवारण

213. जब कूटनीति विफल हो जाती है और राज्य बल का प्रयोग करते हैं, तो यह किस प्रक्रिया की विफलता का प्रतिनिधित्व करता है?
(A) शस्त्रों की दौड़
(B) गठबंधन निर्माण
(C) राष्ट्रीय हित का निर्धारण
(D) विवादों का शांतिपूर्ण समाधान

214. अंतर्राष्ट्रीय कानून में 'संप्रभुता' की अवधारणा का अर्थ है:
(A) पड़ोसी देशों पर आक्रमण करने का अधिकार।
(B) स्वयं राज्य से ऊपर किसी उच्च सत्ता की अनुपस्थिति।
(C) सैन्य गठबंधन में शामिल होने का दायित्व।
(D) सभी मामलों में घरेलू कानून पर अंतर्राष्ट्रीय कानून की श्रेष्ठता।

215. "पवित्र भूमि" पर दावों के कारण या धार्मिक उग्रवाद से प्रेरित युद्ध किस प्रकार का कारण होगा?
(A) मुख्य रूप से आर्थिक
(B) व्यवस्थागत
(C) वैचारिक/धार्मिक
(D) भौगोलिक

216. दुनिया के लगभग प्रत्येक देश द्वारा हस्ताक्षरित एक संधि, जो एक निश्चित प्रकार के हथियार पर प्रतिबंध लगाती है, किसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का एक प्रमुख उदाहरण है:
(A) शस्त्रों की दौड़
(B) हस्तक्षेप
(C) राष्ट्रीय हित को बढ़ावा देना
(D) शस्त्र नियंत्रण या निरस्त्रीकरण

217. निर्णय-प्रक्रिया दृष्टिकोण में, 'तर्कसंगत अभिनेता मॉडल' मानता है कि:
(A) राज्य एक एकल, सुसंगत इकाई के रूप में कार्य करता है जो अपने रणनीतिक उद्देश्यों को अधिकतम करने के लिए विकल्प चुनता है।
(B) निर्णय नौकरशाही की अंदरूनी कलह का परिणाम होते हैं।
(C) नेता अक्सर तर्कहीन होते हैं और भावनाओं से प्रेरित होते हैं।
(D) धारणाएं और गलत धारणाएं सबसे महत्वपूर्ण कारक हैं।

218. निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन शामिल हैं, जिन्हें अभिकथन (A) और कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है। इन दोनों कथनों का सावधानीपूर्वक परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:
अभिकथन (A): वैश्वीकरण को राष्ट्रीय पहचान और संस्कृति के लिए खतरे के रूप में देखा जा सकता है।
कारण (R): मीडिया, उपभोक्ता उत्पादों और विचारों का वैश्विक प्रवाह सांस्कृतिक समरूपीकरण की ओर ले जा सकता है और स्थानीय परंपराओं को चुनौती दे सकता है।
(A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(D) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

219. किसी राज्य द्वारा परमाणु हथियारों के अधिग्रहण को अक्सर उसके नेताओं द्वारा किसके साधन के रूप में उचित ठहराया जाता है:
(A) वैश्विक निरस्त्रीकरण को बढ़ावा देना।
(B) गुटनिरपेक्षता की आवश्यकताओं को पूरा करना।
(C) निवारण के माध्यम से राष्ट्रीय अस्तित्व सुनिश्चित करना।
(D) अंतर्राष्ट्रीय संधि कानून का पालन करना।

NODIA

220. "विचारधारा का अर्थ, भूमिका और प्रासंगिकता" शीतयुद्ध जैसे संघर्षों को समझने के लिए महत्वपूर्ण है, जिसे किसके बीच संघर्ष के रूप में प्रस्तुत किया गया था:
(A) पूंजीवाद और लोकतंत्र बनाम साम्यवादी व्यवस्था।
(B) क्षेत्रीय सीमा विवाद में दो प्रतिद्वंद्वी जातीय समूह।
(C) उन्हीं सीमित प्राकृतिक संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले दो राज्य।
(D) वैश्विक उत्तर और दक्षिण के बीच आर्थिक प्रतिस्पर्धा।

221. अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का कौन सा दृष्टिकोण इस बात से सर्वाधिक चिंतित होगा कि दो राज्यों के बीच संचार में "संकट" को कैसे परिभाषित और निरूपित किया गया है?
(A) यथार्थवादी
(B) व्यवस्था
(C) खेल सिद्धांत
(D) संचार

222. अंतर्राष्ट्रीय कानून में राज्य का सबसे मौलिक अधिकार किसका अधिकार है:
(A) हस्तक्षेप
(B) अस्तित्व और आत्म-संरक्षण
(C) शस्त्रों की दौड़
(D) वैश्वीकरण

(D) कूटनीति

270. राज्य की नीति में वृद्धि के तार्किक क्रम में निम्नलिखित घटनाओं को व्यवस्थित कीजिए:
1. सैन्य बल का उपयोग (युद्ध)
2. राजनयिक विरोध
3. आर्थिक प्रतिबंध आरोपित करना
4. राजनयिक संबंध विच्छेद करना
(A) 2, 4, 3, 1
(B) 1, 2, 3, 4
(C) 2, 3, 1, 4
(D) 3, 4, 2, 1

271. यथार्थवादी सिद्धांत के अनुसार, शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है?
(A) सांस्कृतिक आकर्षण
(B) नैतिक प्राधिकार
(C) अंतर्राष्ट्रीय कानूनी दर्जा
(D) सैन्य और आर्थिक क्षमता

272. युद्ध के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक प्रमुख उद्देश्य है:
(A) इसका प्रचार और प्रोत्साहन
(B) इसकी रोकथाम और उन्मूलन
(C) इसका महिमामंडन
(D) इसका विस्तार

273. नाटो जैसे गठबंधनों के गठन का प्राथमिक कारण था:
(A) सदस्यों के बीच मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना।
(B) एक नई वैश्विक मुद्रा बनाना।
(C) बोधित खतरे के विरुद्ध सामूहिक सुरक्षा प्रदान करना।
(D) गुटनिरपेक्षता के उद्देश्य को आगे बढ़ाना।

274. "एकध्रुवीय" व्यवस्था की अवधारणा किस अंतर्राष्ट्रीय संरचना को संदर्भित करती है जिसका प्रभुत्व किसके पास हो:
(A) दो महाशक्तियाँ
(B) कई महान शक्तियाँ
(C) अंतर्राष्ट्रीय संगठन
(D) एक अकेली महान शक्ति

275. यदि कोई राज्य नेता कहता है, "हमें सहयोग और कानून पर आधारित विश्व बनाना चाहिए, न कि संघर्ष और शक्ति पर," तो वे किस दृष्टिकोण के केंद्र में एक भावना व्यक्त कर रहे हैं?
(A) आदर्शवादी
(B) यथार्थवादी
(C) व्यवस्था
(D) खेल सिद्धांत

276. किसी संघर्ष में क्लोरीन या मस्टर्ड गैस जैसे रासायनिक हथियारों का उपयोग उसे क्या बना देगा:
(A) परमाणु युद्ध
(B) जैव-रासायनिक युद्ध
(C) पारंपरिक युद्ध
(D) व्यवस्थागत युद्ध

277. नियमों और सिद्धांतों का वह निकाय जिसे राज्य एक-दूसरे के साथ अपने संबंधों में कानूनी रूप से बाध्यकारी मानते हैं, वह है:
(A) राष्ट्रीय हित
(B) विचारधारा
(C) अंतर्राष्ट्रीय कानून
(D) शक्ति की राजनीति

278. निम्नलिखित प्रश्न में दो कथन शामिल हैं, जिन्हें अभिकथन (A) और कारण (R) के रूप में अंकित किया गया है। इन दोनों कथनों का सावधानीपूर्वक परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:
अभिकथन (A): निर्णय-प्रक्रिया दृष्टिकोण अध्ययन करता है कि राज्य के भीतर विदेश नीति के विकल्प कैसे बनाए जाते हैं।
कारण (R): यह दृष्टिकोण इस विचार को खारिज करता है कि राज्य एक अखंड इकाई है और इसके बजाय व्यक्तियों, समूहों और नौकरशाहों की भूमिकाओं की जांच करता है।
(A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
(D) A असत्य है लेकिन R सत्य है।

279. अपनी सैन्य शक्ति का उपयोग करने की एक शक्तिशाली राज्य की क्षमता पर एक सीमा अंतर्राष्ट्रीय निंदा का भय और एक बहिष्कृत राज्य बनना हो सकता है। यह सीमा किस पर आधारित है:
(A) मूर्त शक्ति
(B) सैन्य उपकरणों की कमी
(C) आर्थिक पतन
(D) मानकीय और प्रतिष्ठा संबंधी लागत

280. किसी देश के भीतर एक गृहयुद्ध जो रणनीतिक हितों और जातीय संबंधों के कारण पड़ोसी राज्यों और प्रमुख शक्तियों को खींचता है, वह किसके बीच संबंध को दर्शाता है:
(A) जातीय विवाद और व्यापक अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष
(B) निरस्त्रीकरण और शांति
(C) गुटनिरपेक्षता और अलगाव
(D) संधि कानून और इसका सार्वभौमिक अनुप्रयोग

281. 'देतांत' शब्द, जो अक्सर शीतयुद्ध के संदर्भ में उपयोग किया जाता है, किस अवधि को संदर्भित करता है:
(A) बढ़ी हुई शत्रुता और शस्त्रों की दौड़।
(B) सोवियत संघ का अंतिम पतन।
(C) महाशक्तियों के बीच तनाव में कमी और बेहतर राजनयिक संबंध।
(D) गुटनिरपेक्ष आंदोलन का चरमोत्कर्ष।

Click Here to Buy book on Amazon

कथन II: शीतयुद्ध के बाद के युग की विशेषता जातीय विवादों और आतंकवाद सहित नए प्रकार के संघर्षों और सुरक्षा खतरों से रही है।
(A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं।
(C) कथन I सत्य है, लेकिन कथन II असत्य है।
(D) कथन I असत्य है, लेकिन कथन II सत्य है।

235. एक राज्य जो अपनी सुरक्षा और हितों को अन्य सभी चीजों से ऊपर प्राथमिकता देता है, और अन्य राज्यों को संदेह की दृष्टि से देखता है, वह किसके सिद्धांतों के अनुसार कार्य कर रहा है:
(A) आदर्शवाद
(B) संचार सिद्धांत
(C) यथार्थवाद
(D) गुटनिरपेक्षता

236. अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अनुनय, वार्ता और समझौते का उपयोग किसकी पहचान है:
(A) कूटनीति
(B) हस्तक्षेप
(C) निवारण
(D) शस्त्रों की दौड़

237. दूसरे राज्य की क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन न करने का राज्य का मौलिक कर्तव्य किसका आधार है:
(A) वैश्वीकरण की अवधारणा।
(B) गुटनिरपेक्षता की नीति।
(C) खेल सिद्धांत।
(D) अंतर्राष्ट्रीय कानून।

238. यह तर्क कि विदेश नीति के निर्णय पूर्णतः तर्कसंगत नहीं होते हैं, बल्कि प्रतिस्पर्धी नौकरशाही हितों के बीच एक समझौता होते हैं, किसका एक प्रमुख विचार है:
(A) यथार्थवादी दृष्टिकोण
(B) निर्णय-प्रक्रिया दृष्टिकोण
(C) आदर्शवादी दृष्टिकोण
(D) व्यवस्था दृष्टिकोण

239. "शक्ति का अधिग्रहण, उपयोग और सीमाएँ" किस विचारधारा का एक केंद्रीय विषय है?
(A) आदर्शवाद
(B) संचार सिद्धांत
(C) यथार्थवाद
(D) खेल सिद्धांत

240. शीतयुद्ध के दौरान गठबंधन बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था?
(A) आर्थिक वैश्वीकरण को बढ़ावा देना।
(B) गुटनिरपेक्षता को प्रोत्साहित करना।
(C) पूर्ण निरस्त्रीकरण की दिशा में कार्य करना।
(D) विरोधी गुट के विरुद्ध एक सामूहिक रक्षा बनाना।

241. गलत कथन की पहचान कीजिए।
(A) राष्ट्रीय हित सदैव विशुद्ध रूप से नैतिक और परोपकारी शब्दों में परिभाषित किया जाता है।
(B) राष्ट्रीय हित अस्तित्व और कल्याण के लिए राज्य के लक्ष्यों के बारे में है।
(C) राष्ट्रीय हित की धारणा विचारधारा द्वारा आकार ले सकती है।
(D) राष्ट्रीय हित को बढ़ावा देने में कूटनीति या बल प्रयोग शामिल हो सकता है।

242. एक संघर्ष जो कई प्रमुख शक्तियों को खींचता है और पूरी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बदलने की क्षमता रखता है, उसे किस रूप में वर्णित किया जा सकता है:
(A) सीमित युद्ध
(B) व्यवस्थागत युद्ध
(C) पुलिस कार्रवाई
(D) लघु जातीय विवाद

243. शीतयुद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय कानून और सामूहिक सुरक्षा पर आधारित एक "नई विश्व व्यवस्था" बनाने का विचार किस विचारधारा की अभिव्यक्ति था?
(A) यथार्थवादी
(B) व्यवस्था
(C) आदर्शवादी
(D) खेल सिद्धांत

244. कौन सी अवधारणा यह सबसे अच्छा समझाती है कि कोई राज्य अपनी सेना बढ़ाने के बावजूद स्वयं को कम सुरक्षित क्यों अनुभव कर सकता है, क्योंकि उसके पड़ोसी भी ऐसा ही कर रहे हैं?
(A) गुटनिरपेक्षता
(B) शांतिपूर्ण समाधान
(C) संधि कानून
(D) सुरक्षा दुविधा

245. विवादों के शांतिपूर्ण समाधान में कूटनीति की क्या भूमिका है?
(A) यह संचार, वार्ता और समझौते का प्राथमिक साधन है।
(B) यह अप्रासंगिक है, क्योंकि विवाद केवल बल द्वारा सुलझाए जाते हैं।
(C) इसकी एकमात्र भूमिका युद्ध की घोषणा करना है।
(D) यह हस्तक्षेप का एक उपकरण है।

246. बाहरी नियंत्रण से मुक्त होने के राज्य के अधिकार को कहा जाता है:
(A) हस्तक्षेप
(B) संप्रभुता
(C) निवारण
(D) वैश्वीकरण

Downloaded from www.pdf.tube

223. "विभिन्न देशों के लोगों, कंपनियों और सरकारों के बीच अंतःक्रिया और एकीकरण की प्रक्रिया" किसकी एक उपयुक्त परिभाषा है:
(A) शीतयुद्ध
(B) गठबंधन
(C) वैश्वीकरण
(D) हस्तक्षेप

224. सूची I में दिए गए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के शब्द को सूची II में उसकी विपरीत अवधारणा के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:
सूची I: (शब्द)
P. शस्त्रों की दौड़
Q. हस्तक्षेप
R. गठबंधन
S. युद्ध
सूची II: (विपरीत अवधारणा)
1. गुटनिरपेक्षता
2. शांतिपूर्ण समाधान
3. निरस्त्रीकरण
4. संप्रभुता
कूट:
(A) P-1, Q-2, R-4, S-3
(B) P-3, Q-4, R-1, S-2
(C) P-2, Q-3, R-1, S-4
(D) P-3, Q-1, R-4, S-2

225. निवारण की नीति केवल तभी विश्वसनीय होती है जब:
(A) राज्य के पास प्रतिशोध की क्षमता और उसका उपयोग करने की बोधित इच्छा दोनों हो।
(B) राज्य सार्वजनिक रूप से बल प्रयोग का त्याग करता है।
(C) राज्य के पास कोई परमाणु हथियार नहीं हो।
(D) राज्य ने अपनी सेना को भंग कर दिया हो।

226. एक आदर्शवादी तर्क देगा कि विचारधारा की प्रासंगिकता:
(A) केवल शक्ति की राजनीति को उचित ठहराने के लिए है।
(B) शांति को बढ़ावा देने वाले तर्कसंगत संस्थानों और कानूनों द्वारा इसे दूर किया जा सकता है।
(C) सभी राज्य गणनाओं में सबसे महत्वपूर्ण कारक है।
(D) 21वीं सदी में अस्तित्वहीन है।

227. लोकतंत्र में राष्ट्रीय हित के निर्धारण में अक्सर शामिल होता है:
(A) केवल सर्वोच्च नेता की इच्छा।
(B) बिना किसी परिवर्तन के प्राचीन परंपराओं का पालन।
(C) नीतियों का यादृच्छिक चयन।
(D) सार्वजनिक बहस, विशेषज्ञ राय और राजनीतिक नेतृत्व की एक प्रक्रिया।

228. शीतयुद्ध ने नाटो और वारसॉ पैक्ट जैसे प्रतिद्वंद्वी _____ की व्यवस्था बनाई।
(A) गुटनिरपेक्ष आंदोलनों
(B) गठबंधनों
(C) निरस्त्रीकरण समितियों
(D) वैश्वीकरण पहलों

229. निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख प्रश्न है जिसे निर्णय-प्रक्रिया दृष्टिकोण द्वारा संबोधित किया जाता है?
(A) अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में शक्ति का वितरण क्या है?
(B) वे सार्वभौमिक नैतिक नियम क्या हैं जो राज्यों को शासित करने चाहिए?
(C) विदेश नीति के निर्णय कौन और कैसे लेता है?
(D) दो देशों के बीच रणनीतिक खेल में लाभ क्या हैं?

230. राज्य की शक्ति के तत्वों के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए:
1. मूर्त तत्व, जैसे सैन्य बल और आर्थिक आकार।
2. अमूर्त तत्व, जैसे राष्ट्रीय मनोबल और नेतृत्व की गुणवत्ता।
3. वैचारिक तत्व, जैसे इसकी राजनीतिक व्यवस्था का आकर्षण।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं?
(A) केवल 1
(B) केवल 1 और 2
(C) केवल 2 और 3
(D) 1, 2 और 3

231. आदर्शवादी परंपरा के अनुसार, युद्ध की रोकथाम भारी रूप से किस पर निर्भर करती है:
(A) शक्ति संतुलन
(B) स्वयं-सहायता का सिद्धांत
(C) परमाणु विनाश का निरंतर खतरा
(D) अंतर्राष्ट्रीय कानून और संस्थानों का विकास

232. वह युद्ध जो सैनिकों और टैंकों के साथ नहीं, बल्कि वायरस और विषाक्त पदार्थों के साथ लड़ा जाता है, वह है:
(A) पारंपरिक युद्ध
(B) जैव-रासायनिक युद्ध
(C) परमाणु युद्ध
(D) व्यवस्थागत युद्ध

233. यह सिद्धांत कि संधियों का सद्भावनापूर्वक पालन किया जाना चाहिए, किसका केंद्र है:
(A) निवारण सिद्धांत
(B) यथार्थवादी दृष्टिकोण
(C) संधि कानून
(D) शस्त्रों की दौड़ की अवधारणा

234. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन I: शीतयुद्ध के अंत का अर्थ विश्व में सभी बड़े संघर्षों का अंत था।

NODIA

हिंसक होती है।
(B) कोई कार्यात्मक अंतर नहीं है; दोनों शब्दों का उपयोग एक-दूसरे के स्थान पर किया जाता है।
(C) हस्तक्षेप सभी मामलों में कानूनी है, जबकि कूटनीति सख्त रूप से अवैध है।
(D) हस्तक्षेप बलपूर्वक होता है, जबकि कूटनीति वार्ता पर आधारित होती है।

258. अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का इस परिप्रेक्ष्य से अध्ययन कि कैसे समग्र व्यवस्था राज्यों के व्यवहार को प्रतिबंधित और आकार देती है, किसका मूल है:
(A) व्यवस्था दृष्टिकोण
(B) निर्णय-प्रक्रिया दृष्टिकोण
(C) आदर्शवादी दृष्टिकोण
(D) संचार दृष्टिकोण

259. किसी राज्य की शक्ति 'सीमित' मानी जाती है क्योंकि:
(A) इसका उपयोग करना सदैव नैतिक रूप से त्रुटिपूर्ण होता है।
(B) शक्ति एक भ्रम है और वास्तव में इसका कोई अस्तित्व नहीं है।
(C) अन्य राज्य इसके विरुद्ध संतुलन बनाने के लिए कार्य कर सकते हैं, और इसके उपयोग में लागत आती है।
(D) अंतर्राष्ट्रीय कानून ने शक्ति के उपयोग को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है।

260. युद्ध के संभावित कारणों के रूप में निम्नलिखित पर विचार कीजिए:
1. युद्ध क्षेत्र को लेकर विवादों के कारण हो सकते हैं।
2. युद्ध विचारधाराओं के बीच संघर्ष के कारण हो सकते हैं।
3. युद्ध जातीय तनाव और आत्मनिर्णय की खोज के कारण हो सकते हैं।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3

261. निवारण की अवधारणा किस प्रकार के हथियारों के साथ सबसे निकटता से जुड़ी हुई है?
(A) पारंपरिक तोपखाने
(B) जैव-रासायनिक एजेंट
(C) छोटे हथियार
(D) परमाणु हथियार

262. यथार्थवादी सिद्धांत में "अराजकता" का अर्थ है:
(A) अव्यवस्था और विकार
(B) राज्यों के ऊपर किसी केंद्रीय सत्ता की अनुपस्थिति
(C) नियमों के बिना एक विश्व
(D) विश्व सम्राट द्वारा शासित व्यवस्था

263. जैविक हथियारों के उत्पादन और भंडारण पर प्रतिबंध लगाने का अंतर्राष्ट्रीय समझौता किसका एक कार्य है:
(A) निवारण
(B) शस्त्रों की दौड़
(C) निरस्त्रीकरण या शस्त्र नियंत्रण
(D) हस्तक्षेप

264. गठबंधनों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन I: गठबंधन आपसी सैन्य सहायता के उद्देश्य से राज्यों के औपचारिक संघ हैं।
कथन II: गुटनिरपेक्षता की नीति गठबंधन का एक स्वरूप है।
(A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं।
(C) कथन I सत्य है, लेकिन कथन II असत्य है।
(D) कथन I असत्य है, लेकिन कथन II सत्य है।

265. "राष्ट्रीय हित को बढ़ावा देना" उन कार्यों को संदर्भित करता है जो एक राज्य किसके लिए करता है:
(A) अपने विदेश नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करना।
(B) अपनी ही अर्थव्यवस्था को निर्बल करना।
(C) स्वयं को विश्व से पृथक करना।
(D) बिना किसी प्रश्न के अन्य राज्यों के नेतृत्व का अनुसरण करना।

266. एक राज्य जो व्यापार सौदे पर वार्ता करने के लिए अपने विदेश मंत्री को भेज रहा है, वह किसमें संलग्न है:
(A) हस्तक्षेप
(B) कूटनीति
(C) निवारण
(D) युद्ध

267. अंतर्राष्ट्रीय कानून में संप्रभु उन्मुक्ति का सिद्धांत किस अवधारणा का प्रत्यक्ष परिणाम है?
(A) वैश्वीकरण
(B) शस्त्रों की दौड़
(C) गुटनिरपेक्षता
(D) संप्रभु समान के रूप में राज्य

268. कौन सा सिद्धांत आकस्मिक युद्ध की ओर ले जाने में गलत धारणा या त्रुटिपूर्ण सूचना की भूमिका में सर्वाधिक रुचि रखेगा?
(A) संचार सिद्धांत
(B) यथार्थवादी सिद्धांत
(C) व्यवस्था सिद्धांत
(D) आदर्शवादी सिद्धांत

269. शीतयुद्ध के अंत ने कई देशों के लिए किस प्रमुख विदेश नीति रुख की प्रासंगिकता को चुनौती दी?
(A) वैश्वीकरण
(B) हस्तक्षेप
(C) गुटनिरपेक्षता

Click Here to Buy book on Amazon

अभिनेताओं पर निर्भर करती है।
(C) विशुद्ध रूप से एक सैन्य घटना।
(D) वैश्वीकरण के युग में एक पुरानी विचार धारा।

294. वह कानूनी सिद्धांत कि किसी राज्य पर उसकी सहमति के बिना दूसरे राज्य की अदालतों में अभियोग नहीं चलाया जा सकता है, किसकी अभिव्यक्ति है:
(A) हस्तक्षेप
(B) गठबंधन प्रतिबद्धता
(C) संप्रभुता
(D) विचारधारा

295. कौन सा सिद्धांत यह मानता है कि राज्य बिलियर्ड गेंदों की तरह हैं, जिनकी गति अन्य गेंदों के साथ उनके टकराव से निर्धारित होती है, न कि उनके आंतरिक स्वरूप से?
(A) निर्णय-प्रक्रिया सिद्धांत
(B) संचार सिद्धांत
(C) आदर्शवाद
(D) व्यवस्था सिद्धांत

296. दो राज्यों द्वारा हस्ताक्षरित संधि _____ है, जबकि कई राज्यों द्वारा हस्ताक्षरित संधि _____ है।
(A) द्विपक्षीय; बहुपक्षीय
(B) बहुपक्षीय; द्विपक्षीय
(C) अवैध; कानूनी
(D) यथार्थवादी; आदर्शवादी

297. 2001 के बाद आतंकवाद के विरुद्ध वैश्विक संघर्ष, जिसमें राज्यों का गठबंधन सम्मिलित था, को एक गैर-राज्य अभिनेता के विरुद्ध एक नए प्रकार के _____ के गठन के रूप में देखा जा सकता है।
(A) गुटनिरपेक्षता
(B) गठबंधन
(C) निरस्त्रीकरण समझौता
(D) द्विध्रुवीय व्यवस्था

298. यह तर्क कि पूंजीवाद का प्रसार एक वैश्वीकृत आर्थिक व्यवस्था बनाता है जो राज्य की संप्रभुता पर प्रभावी हो जाती है, किसके अध्ययन का एक प्रमुख विषय है:
(A) शीतयुद्ध
(B) निवारण
(C) वैश्वीकरण
(D) गुटनिरपेक्षता

299. शस्त्रों की दौड़ का प्राथमिक कारण है:
(A) आपसी विश्वास और सहयोग
(B) एक सफल निरस्त्रीकरण संधि
(C) अंतर्राष्ट्रीय कानून की प्रभावशीलता
(D) सुरक्षा दुविधा और पारस्परिक संदेह

300. सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था की स्थापना के माध्यम से युद्ध की रोकथाम और उन्मूलन किसका एक मुख्य लक्ष्य है:
(A) यथार्थवादी शक्ति राजनीति।
(B) आदर्शवादी परंपरा और संयुक्त राष्ट्र जैसे संगठन।
(C) गुटनिरपेक्ष आंदोलन।
(D) शस्त्रों की दौड़ की अवधारणा।

NODIA
www.nodia.in

282. राष्ट्रीय हित का 'निर्धारण' एक ऐसी प्रक्रिया है जो मुख्य रूप से है:
(A) घरेलू
(B) अंतर्राष्ट्रीय
(C) न्यायिक
(D) अप्रासंगिक

283. कौन सा सिद्धांत यह सुझाव देगा कि संयुक्त राष्ट्र को सुदृढ़ करके और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून को बढ़ावा देकर युद्ध को रोका जा सकता है?
(A) यथार्थवाद
(B) व्यवस्था सिद्धांत
(C) खेल सिद्धांत
(D) आदर्शवाद

284. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:
सूची I: (अवधारणा)
P. संप्रभुता
Q. हस्तक्षेप
R. गठबंधन
S. निरस्त्रीकरण
सूची II: (विशेषता)
1. पारस्परिक रक्षा प्रतिबद्धता
2. शस्त्रों की कमी
3. राज्य का सर्वोच्च प्राधिकार
4. बलपूर्वक हस्तक्षेप
कूट:
(A) P-3, Q-4, R-1, S-2
(B) P-4, Q-3, R-2, S-1
(C) P-3, Q-1, R-4, S-2
(D) P-1, Q-2, R-3, S-4

285. किसी राष्ट्र का 'प्रकट नियति' या 'स्वतंत्र विश्व के नेता' के रूप में अपनी भूमिका में विश्वास इस बात का उदाहरण है कि कैसे _____ उसके राष्ट्रीय हित और विदेश नीति को आकार दे सकती है।
(A) संधि कानून
(B) निरस्त्रीकरण
(C) विचारधारा
(D) निवारण

286. विवादों के शांतिपूर्ण समाधान में मध्यस्थता और अधिनिर्णय के बीच मुख्य अंतर क्या है?
(A) मध्यस्थता बाध्यकारी है, जबकि अधिनिर्णय नहीं।
(B) अधिनिर्णय का परिणाम एक बाध्यकारी निर्णय होता है, जबकि मध्यस्थता एक सुगम वार्ता है।
(C) मध्यस्थता में सैन्य बल शामिल होता है, जबकि अधिनिर्णय में नहीं।
(D) दोनों शब्दों के बीच कोई अंतर नहीं है।

287. शीतयुद्ध के अंत ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में पुनर्विचार की अवधि को जन्म दिया, जिसमें _____ नए युग के एक प्रमुख विषय के रूप में उभरा।
(A) द्विध्रुवीयता
(B) शस्त्रों की दौड़
(C) वारसॉ पैक्ट
(D) वैश्वीकरण

288. किसी राज्य के क्षेत्रीय अखंडता के अधिकार को किसके तहत संरक्षित किया जाता है:
(A) शस्त्रों की दौड़ का सिद्धांत
(B) अंतर्राष्ट्रीय कानून
(C) हस्तक्षेप की अवधारणा
(D) खेल सिद्धांत

289. एक बड़ी, सुसज्जित सेना का स्वामित्व शक्ति का एक _____ तत्व है।
(A) अमूर्त
(B) वैचारिक
(C) मूर्त
(D) संचारी

290. राष्ट्रीय हित के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए:
1. राज्य की सुरक्षा और अस्तित्व।
2. राष्ट्र की आर्थिक समृद्धि।
3. राष्ट्र के मूल्यों और विचारधारा को बढ़ावा देना।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3

291. निम्नलिखित में से कौन शीतयुद्ध की विशेषता नहीं है?
(A) महाशक्तियों के विरुद्ध गुटनिरपेक्ष राज्यों का वैश्विक गठबंधन
(B) द्विध्रुवीय अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था
(C) वैचारिक प्रतिस्पर्धा
(D) परोक्ष युद्ध और शस्त्रों की दौड़

292. युद्ध में जाने के निर्णय का अध्ययन कैसे विभिन्न सैन्य शाखाओं और सरकारी विभागों के प्रतिस्पर्धी हितों से प्रभावित हुआ, यह किस दृष्टिकोण के अंतर्गत आता है?
(A) व्यवस्था दृष्टिकोण
(B) यथार्थवादी दृष्टिकोण
(C) आदर्शवादी दृष्टिकोण
(D) निर्णय-प्रक्रिया दृष्टिकोण

293. अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में 'शक्ति' की अवधारणा को सबसे अच्छी तरह इस प्रकार समझा जा सकता है:
(A) एक निश्चित मात्रा जिसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता।
(B) एक संबंधात्मक अवधारणा, जो संदर्भ और शामिल

Downloaded from www.pdf.tube

(D) कथन I असत्य है, लेकिन कथन II सत्य है।

200. अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत राज्यों के मौलिक कर्तव्यों के रूप में निम्नलिखित पर विचार कीजिए:
1. अन्य राज्यों की संप्रभुता का सम्मान करना।
2. विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाना।
3. बल प्रयोग से बचना।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3

201. कौन सा सिद्धांत यह तर्क देगा कि एक अराजक व्यवस्था में भी, राज्य ऐसे संस्थान बना सकते हैं जो अनिश्चितता को कम करके और संचार को सुगम बनाकर सहयोग को बढ़ावा देते हैं?
(A) आदर्शवाद
(B) यथार्थवाद
(C) व्यवस्था सिद्धांत
(D) खेल सिद्धांत

202. शीतयुद्ध के बाद के युग में किस प्रकार के संघर्ष में वृद्धि देखी गई?
(A) महाशक्तियों के बीच वैश्विक परमाणु युद्ध।
(B) जातीय विवादों सहित अंतः-राज्यीय संघर्ष।
(C) स्वतंत्रता के लिए औपनिवेशिक युद्ध।
(D) प्रमुख यूरोपीय शक्तियों के बीच औपचारिक युद्ध।

203. किसी राज्य के राजनयिक कोर, गुप्तचर एजेंसियां और सेना किसके साधन हैं:
(A) पूर्ण निरस्त्रीकरण की खोज।
(B) गुटनिरपेक्षता का अभ्यास।
(C) राष्ट्रीय हित का प्रचार।
(D) युद्ध का उन्मूलन।

204. "बल प्रयोग या धन के स्थान पर आकर्षण के माध्यम से वह प्राप्त करने की क्षमता जो आप चाहते हैं" किसका विवरण है:
(A) सैन्य शक्ति
(B) कठोर शक्ति
(C) आर्थिक शक्ति
(D) मृदु शक्ति

205. अंतर्राष्ट्रीय कानूनी सिद्धांत जो हस्तक्षेप को प्रतिबंधित करता है, वह पूर्ण नहीं है और अक्सर किन मामलों में इस पर बहस होती है:
(A) व्यापार विवाद
(B) सांस्कृतिक आदान-प्रदान की असहमति
(C) कथित गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन
(D) मानक राजनयिक वार्ता

206. 'शस्त्र नियंत्रण' और 'निरस्त्रीकरण' के बीच एक प्रमुख अंतर यह है कि शस्त्र नियंत्रण जोखिम को _____ करना चाहता है, जबकि निरस्त्रीकरण हथियारों को _____ करना चाहता है।
(A) प्रबंधित; समाप्त
(B) बढ़ाना; बढ़ाना
(C) समाप्त; प्रबंधित
(D) अनदेखा; प्रसारित

NODIA

207. युद्ध में जाने के किसी देश के निर्णय का विश्लेषण उसके शीर्ष नेताओं की विश्वदृष्टि और मनोवैज्ञानिक स्थितियों की जांच करके किया जाता है। यह विश्लेषण किसका उपयोग कर रहा है:
(A) व्यवस्था दृष्टिकोण
(B) यथार्थवादी दृष्टिकोण
(C) आदर्शवादी दृष्टिकोण
(D) निर्णय-प्रक्रिया दृष्टिकोण

208. गुटनिरपेक्षता की नीति किसकी प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया थी?
(A) वैश्वीकरण का उदय।
(B) शीतयुद्ध की द्विध्रुवीय संरचना।
(C) संयुक्त राष्ट्र की स्थापना।
(D) यूरोपीय एकीकरण की प्रक्रिया।

209. किसी राज्य द्वारा दूसरे परमाणु राज्य के हमले को रोकने के उद्देश्य से एक विशाल परमाणु शस्त्रागार का अस्तित्व ही किस नीति का उदाहरण है:
(A) निरस्त्रीकरण
(B) हस्तक्षेप
(C) निवारण
(D) गुटनिरपेक्षता

210. अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में निम्नलिखित वैचारिक विकासों को उनकी प्रमुखता के सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए:
1. द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शक्ति की राजनीति पर यथार्थवादी ध्यान।
2. प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के माध्यम से शांति की आदर्शवादी आशाएं।
3. शीतयुद्ध के बाद वैश्वीकरण और गैर-राज्य अभिनेताओं पर ध्यान।
4. शीतयुद्ध के दौरान एक अवधारणा के रूप में गुटनिरपेक्षता का उदय।

(A) 2, 1, 4, 3
(B) 1, 2, 3, 4
(C) 2, 4, 1, 3
(D) 3, 1, 2, 4

211. निम्नलिखित में से कौन यथार्थवादी विचारधारा की एक मुख्य धारणा है?
(A) अंतर्राष्ट्रीय संस्थान शांति लागू कर सकते हैं।
(B) राज्य सुरक्षा के ऊपर सहयोग को प्राथमिकता देते हैं।

उत्तर (व्याख्या सहित)

1. (B) आदर्शवादी दृष्टिकोण
अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का आदर्शवादी दृष्टिकोण विश्व शांति हेतु नैतिक मूल्यों और आदर्शों की प्रधानता पर बल देता है। यह विचारधारा मानती है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और वैश्विक संगठनों के सुदृढ़ीकरण से युद्धों को प्रभावी रूप से रोका जा सकता है। सामूहिक सुरक्षा और सहयोग के माध्यम से न्यायपूर्ण व्यवस्था स्थापित करना इसका मुख्य लक्ष्य है। इससे मानव समाज संघर्ष के बजाय शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की दिशा में निरंतर अग्रसर हो सकता है।

2. (A) संप्रभु राज्य
यथार्थवादी दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को संप्रभु राष्ट्रों के बीच शक्ति संघर्ष के रूप में देखता है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य ही वैश्विक व्यवस्था के प्राथमिक अभिनेता हैं, जो अस्तित्व की रक्षा और शक्ति संचय हेतु कार्य करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अराजकता में राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना ही विदेश नीति का सर्वोच्च लक्ष्य है। यहाँ विश्लेषण की इकाई के रूप में केवल संप्रभु राज्यों को केंद्रीय महत्व दिया जाता है, जो अपने हितों की रक्षा करते हैं।

3. (C) कथन I सत्य है, लेकिन कथन II असत्य है।
व्यवस्था दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विश्लेषण एक समग्र इकाई के रूप में करता है जहाँ इकाइयों की परस्पर क्रियाएँ महत्वपूर्ण होती हैं। यह राज्यों के व्यक्तिगत व्यवहार के बजाय संपूर्ण वैश्विक ढांचे के प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करता है। कथन II गलत है क्योंकि निर्णय लेने वालों की मनोवैज्ञानिक प्रेरणाओं का अध्ययन निर्णय-प्रक्रिया दृष्टिकोण के अंतर्गत आता है। अतः इस सिद्धांत में संरचनात्मक कारकों को ही विश्लेषण का मुख्य आधार और केंद्र माना जाता है।

4. (D) रणनीतिक अंतःक्रियाओं का मॉडल तैयार करना जहाँ परिणाम सभी के विकल्पों पर निर्भर करते हैं।
खेल सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में रणनीतिक निर्णय लेने की प्रक्रिया का गणितीय और तर्कसंगत विश्लेषण करता है। इसमें माना जाता है कि एक राज्य का निर्णय और उससे प्राप्त परिणाम दूसरे प्रतिस्पर्धी राज्यों के संभावित विकल्पों पर निर्भर करते हैं। यह दृष्टिकोण जटिल परिस्थितियों में लाभ को अधिकतम करने और जोखिम कम करने हेतु विभिन्न मॉडलों का उपयोग करता है। यह संघर्ष और सहयोग की स्थितियों में राज्य के व्यवहार को समझने में सहायक है।

5. (C) यह सभी परिस्थितियों में राज्य को एक एकात्मक, तर्कसंगत अभिनेता के रूप में मानता है।
निर्णय-प्रक्रिया दृष्टिकोण इस विचार को चुनौती देता है कि राज्य सदैव एक एकात्मक और पूरी तरह तर्कसंगत अभिनेता के रूप में कार्य करता है। इसके बजाय, यह विदेश नीति निर्माण में शामिल विभिन्न व्यक्तियों, समूहों और नौकरशाही संगठनों की भूमिका पर प्रकाश डालता है। यह विश्लेषण करता है कि कैसे आंतरिक राजनीति और मनोवैज्ञानिक कारक निर्णयों को प्रभावित करते हैं। राज्य को एकल इकाई मानना यथार्थवाद की विशेषता है, जबकि यह दृष्टिकोण आंतरिक जटिलताओं का सूक्ष्म अध्ययन करता है।

6. (B) राष्ट्रीय शक्ति के एक विशिष्ट तत्व का अधिग्रहण और उपयोग करना।
जब कोई छोटा राष्ट्र अपनी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति या महत्वपूर्ण संसाधन पर नियंत्रण का उपयोग शक्तिशाली देशों को प्रभावित करने हेतु करता है, तो यह राष्ट्रीय शक्ति का व्यावहारिक प्रयोग है। राष्ट्रीय शक्ति केवल सैन्य क्षमता तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें रणनीतिक स्थिति और संसाधनों का कुशल उपयोग भी शामिल है। यह दर्शाता है कि कैसे राष्ट्र अपने उपलब्ध संसाधनों को कूटनीतिक प्रभाव और सौदेबाजी की शक्ति में बदलकर लाभ प्राप्त करते हैं।

7. (D) वे लक्ष्य जिन्हें एक राज्य अपनी सुरक्षा और राष्ट्रीय कल्याण सुनिश्चित करने के लिए अपनाता है।
राष्ट्रीय हित किसी भी देश की विदेश नीति का आधारभूत मार्गदर्शक सिद्धांत होता है। यह उन व्यापक लक्ष्यों का समूह है जिन्हें एक राष्ट्र अपनी संप्रभुता की रक्षा, सुरक्षा और आर्थिक समृद्धि के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त करना चाहता है। यह समय और परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित हो सकता है, लेकिन इसका मूल उद्देश्य सदैव राष्ट्र का कल्याण और वैश्विक व्यवस्था में अपनी स्थिति मजबूत करना होता है। नीति निर्माता इसे ध्यान में रखकर ही रणनीतियाँ बनाते हैं।

8. (A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
यथार्थवादी सिद्धांत के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था अराजक है क्योंकि यहाँ राज्यों के ऊपर शासन करने वाली कोई केंद्रीय विश्व सरकार नहीं है। इस अराजकता के कारण राज्यों में असुरक्षा की भावना बनी रहती है, जिससे वे अपनी सुरक्षा और शक्ति को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं। नियमों को लागू करने वाले वैश्विक निकाय के अभाव में प्रत्येक राज्य को स्वयं-सहायता के सिद्धांत पर निर्भर होना पड़ता है। अतः राज्यों की शक्ति के प्रति निरंतर प्रतिस्पर्धा व्यवस्थागत संरचना का परिणाम है।

9. (C) नीति-निर्माण में विचारधारा की पूर्ण अनुपस्थिति।
राष्ट्रीय शक्ति कई तत्वों से मिलकर बनती है जिसमें भूगोल, जनसंख्या, आर्थिक क्षमता, तकनीक और सैन्य शक्ति प्रमुख हैं। विचारधारा भी राष्ट्रीय शक्ति का एक महत्वपूर्ण अमूर्त तत्व है क्योंकि यह नीतियों को दिशा प्रदान करती है और जनता का मनोबल बढ़ाती है। नीति-निर्माण में विचारधारा की पूर्ण अनुपस्थिति शक्ति का तत्व नहीं हो सकती। विचारधारा का

Click Here to Buy book on Amazon

हुआ, जिससे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नए सहयोग और नई सुरक्षा चुनौतियों (जैसे आतंकवाद) का उदय हुआ। यह आधुनिक इतिहास की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और युगांतकारी घटना थी जिसने वैश्विक संरचना को पुनर्गठित किया।

46. (D) यथार्थवाद
यथार्थवादी विचारक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कानून की प्रभावशीलता को लेकर संशयवादी होते हैं। वे मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था अराजक है और यहाँ संप्रभु राज्यों से ऊपर कोई ऐसी सत्ता नहीं है जो कानूनों को बाध्यकारी रूप से लागू कर सके। यथार्थवाद के अनुसार, राष्ट्र केवल तभी कानूनों का पालन करते हैं जब वे उनके हितों के अनुकूल होते हैं। उनके लिए शक्ति ही अंतिम सत्य है और कानून अक्सर शक्तिशाली राज्यों के प्रभुत्व को बनाए रखने का एक उपकरण मात्र होता है। वे राष्ट्रीय सुरक्षा को कानूनी मर्यादाओं से ऊपर रखते हैं।

47. (D) कथन I असत्य है, लेकिन कथन II सत्य है।
राष्ट्रीय हित का निर्धारण कोई वस्तुनिष्ठ या विशुद्ध वैज्ञानिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह गहराई से राजनीतिक है। इसमें विभिन्न घरेलू हित समूहों, राजनीतिक दलों और नौकरशाही संस्थानों के बीच निरंतर विचार-विमर्श की प्रक्रिया शामिल होती है। विभिन्न अभिनेताओं के दृष्टिकोण और प्राथमिकताएं अलग-अलग हो सकती हैं, जो अंततः देश की विदेश नीति की दिशा तय करती हैं। इसलिए, राष्ट्रीय हित कोई स्थिर तथ्य नहीं है, बल्कि यह आंतरिक चर्चा और बाहरी परिस्थितियों के साथ निरंतर विकसित होने वाला एक गतिशील परिणाम है जो नेतृत्व द्वारा आकार लेता है।

48. (B) संप्रभुता का सिद्धांत
संप्रभुता का सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय कानून का वह आधार स्तंभ है जो यह मानता है कि प्रत्येक राज्य अपने क्षेत्र के भीतर सर्वोच्च है और उसे बाहरी हस्तक्षेप के बिना निर्णय लेने का अधिकार है। इसके परिणामस्वरूप, अन्य राज्यों का यह कानूनी कर्तव्य बनता है कि वे किसी राष्ट्र के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करें। यह सिद्धांत राज्यों की स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करता है। संप्रभुता का सम्मान करना ही वैश्विक शांति और राष्ट्रों के बीच शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व को बनाए रखने की पहली अनिवार्य शर्त है। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का मूल आधार है।

49. (B) अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अन्य राज्यों की कार्रवाइयां और संभावित प्रतिक्रियाएं।
किसी भी राज्य की शक्ति पूर्णतः असीमित नहीं होती है। शक्ति के प्रयोग में सबसे बड़ी बाधा अन्य राज्यों की प्रतिक्रिया का भय और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में मौजूद शक्ति संतुलन है। यदि कोई राज्य अपनी शक्ति का अत्यधिक प्रयोग करता है, तो अन्य राष्ट्र उसके विरुद्ध गठबंधन बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त, अंतर्राष्ट्रीय कानून और अपने देश के भीतर संसाधनों की सीमा भी शक्ति को नियंत्रित करती है। अतः शक्ति का प्रयोग सदैव संभावित लागत और लाभ के जटिल विश्लेषण के बाद ही किया जाता है, जिसमें बाहरी वातावरण निर्णायक होता है।

50. (B) केवल 2 और 3
आदर्शवादी दृष्टिकोण इस विश्वास पर आधारित है कि राज्यों के बीच हितों का सामंजस्य संभव है और सहयोग के माध्यम से संघर्षों को टाला जा सकता है। यह विचारधारा अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों और विधिक ढांचे की प्रभावशीलता में गहरा विश्वास रखती है, जो राष्ट्रों के व्यवहार को विनियमित कर सकते हैं। कथन 1 यथार्थवादी विचारधारा की विशेषता है जो अराजकता और शक्ति की राजनीति पर बल देती है, जबकि आदर्शवाद सहयोग को प्राथमिकता देता है। अतः आदर्शवाद मुख्य रूप से विधिक और संस्थागत सुधारों के जरिए वैश्विक शांति की वकालत करता है।

51. (C) जीवित जीव या उनके विषाक्त उत्पाद जिनसे मृत्यु हो सकती है।
जैव-रासायनिक युद्ध संघर्ष का वह रूप है जिसमें सूक्ष्मजीवों (जैसे बैक्टीरिया, वायरस) या जहरीले रसायनों का उपयोग मनुष्यों या फसलों को मारने हेतु किया जाता है। इन्हें 'निर्धन का परमाणु बम' भी कहा जाता है क्योंकि ये तुलनात्मक रूप से कम खर्चीले होते हैं लेकिन व्यापक तबाही मचा सकते हैं। इनका प्रभाव अदृश्य और अनियंत्रित हो सकता है, जिससे निर्दोष नागरिक आबादी को भारी खतरा होता है। इसकी भयावहता के कारण वैश्विक स्तर पर इनके उत्पादन और उपयोग पर संधियों के माध्यम से पूर्ण प्रतिबंध लगाने के निरंतर प्रयास किए गए हैं।

52. (B) सैन्य बल या बल प्रयोग की धमकी
'कठोर शक्ति' (हार्ड पावर) का तात्पर्य उन प्रत्यक्ष और बलपूर्वक उपकरणों से है जिनका उपयोग राज्य अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए करते हैं। इसमें सैन्य बल का प्रयोग, आक्रमण की धमकी या आर्थिक प्रतिबंध जैसे उपाय शामिल हैं जो दूसरे पक्ष को किसी विशेष कार्य हेतु विवश करते हैं। इसके विपरीत, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और कूटनीति 'मृदु शक्ति' के उदाहरण हैं जो आकर्षण पर आधारित होते हैं। कठोर शक्ति का उपयोग अक्सर तब किया जाता है जब शांतिपूर्ण तरीके विफल हो जाते हैं या राष्ट्रीय सुरक्षा को तत्काल खतरा होता है।

53. (D) संचार दृष्टिकोण
संचार दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को सूचना के प्रवाह और निर्णयों के एक नेटवर्क के रूप में देखता है। इसका मुख्य केंद्र यह समझना है कि कैसे राज्य सूचना प्राप्त करते हैं, उसे संसाधित करते हैं और फिर प्रतिक्रिया देते हैं। यह दृष्टिकोण मानता है कि संघर्ष अक्सर गलत धारणाओं या संचार की कमी से उत्पन्न होते हैं। यदि संचार के माध्यम पारदर्शी और प्रभावी हों, तो राष्ट्रों के बीच सहयोग बढ़ सकता है। यह राज्यों को स्वायत्त अभिनेताओं के बजाय सूचना-प्रसंस्करण इकाइयों के रूप में विश्लेषित करने पर बल देता है जो संदेशों के माध्यम से क्रिया करते हैं।

NODIA

54. (A) शीतयुद्ध
शीतयुद्ध वह काल था जिसमें प्रत्यक्ष युद्ध के बिना संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच तीव्र भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता बनी रही। इसकी शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध के समापन के साथ हुई और यह 1991 में सोवियत संघ के विघटन

STUDYING FROM PDFs?

THINK AGAIN.

If you are studying only from PDFs,
you are wasting valuable time.

Research shows that learning from

PRINTED BOOKS has up to

4× HIGHER RETENTION

than studying from screens.

PRINT BOOK = BETTER MEMORY

PDF = LOWER RETENTION

Those who study from **PRINTED BOOKS**
move **AHEAD.**

Others are left **BEHIND**
in competition.

In competitive exams,
being average is not enough.

STAY ONE STEP AHEAD.

19. (C) वैश्वीकरण
वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसने व्यापार, निवेश, संचार और संस्कृति के माध्यम से राष्ट्रों के बीच की दूरियों को कम कर दिया है। इसके कारण आर्थिक और सामाजिक गतिविधियाँ राष्ट्रीय सीमाओं के बंधन से मुक्त होकर वैश्विक स्तर पर संचालित होने लगी हैं। यह परस्पर निर्भरता राज्यों की पूर्ण संप्रभुता को चुनौती देती है और वैश्विक समुदाय को एक साझा मंच प्रदान करती है। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी की प्रगति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे दुनिया एक 'वैश्विक ग्राम' के रूप में परिवर्तित हो गई है।

20. (A) केवल 1 और 2
अंतर्राष्ट्रीय कानून मुख्य रूप से संप्रभु राज्यों के बीच संबंधों को नियंत्रित करता है, जिसमें उनके अधिकार और उत्तरदायित्व शामिल होते हैं। यह संधियों के निर्माण और विवादों के समाधान के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचा प्रदान करता है। कथन 3 गलत है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कानून का प्राथमिक विषय राज्यों के बीच की बाहरी राजनीति है, न कि किसी राज्य की आंतरिक घरेलू राजनीति। यह वैश्विक व्यवस्था में स्थिरता लाने और संघर्षों को कानूनी दायरे में हल करने के लिए नियमों का व्यवस्थित समूह है।

21. (C) अन्य संप्रभु राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार।
अंतर्राष्ट्रीय कानून के बुनियादी सिद्धांतों के अनुसार, प्रत्येक राज्य को संप्रभु समानता, क्षेत्रीय अखंडता और आत्मरक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त है। किसी अन्य देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना इन नियमों का उल्लंघन माना जाता है और यह राज्य का अधिकार नहीं हो सकता। संप्रभुता का अर्थ ही यह है कि एक राज्य अपने आंतरिक विषयों पर निर्णय लेने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। बाहरी शक्तियों को उसमें बाधा डालने की अनुमति नहीं है। हस्तक्षेप न करना ही अंतर्राष्ट्रीय शांति और व्यवस्था का आधार है।

22. (B) एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य के आंतरिक मामलों में बलपूर्वक हस्तक्षेप।
अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में हस्तक्षेप तब होता है जब एक देश किसी दूसरे संप्रभु राष्ट्र की घरेलू नीतियों या कार्यों को बदलने के उद्देश्य से दबाव डालता है या बल प्रयोग करता है। यह संप्रभुता के सिद्धांत का उल्लंघन माना जाता है और इससे संघर्ष की संभावना बढ़ जाती है। हस्तक्षेप के विभिन्न रूप हो सकते हैं, जैसे सैन्य कार्रवाई या प्रत्यक्ष राजनीतिक दबाव। यह क्रिया सामान्य कूटनीतिक संबंधों से भिन्न होती है क्योंकि इसमें स्वेच्छा के बजाय जबरदस्ती या प्रभाव का उपयोग किया जाता है।

23. (D) संधि कानून
संधि कानून अंतर्राष्ट्रीय कानून की वह महत्वपूर्ण शाखा है जो राज्यों के बीच लिखित समझौतों के निर्माण और संचालन से संबंधित नियमों को परिभाषित करती है। संधियाँ राज्यों के बीच सहयोग का मुख्य आधार होती हैं और इनके माध्यम से ही अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों का औपचारिक निर्धारण किया जाता है। इसमें संधियों के अनुसमर्थन, उनके पालन की अनिवार्यता और उल्लंघन की स्थिति में कानूनी परिणामों के प्रावधान शामिल होते हैं। यह वैश्विक व्यवस्था में स्थिरता और विश्वास सुनिश्चित करने के लिए एक अनिवार्य विधिक उपकरण है।

24. (A) यथार्थवादी दृष्टिकोण
जब कोई नेता अपनी विदेश नीति में शक्ति के अर्जन, संचय और संरक्षण को प्राथमिकता देता है, तो वह यथार्थवादी दृष्टिकोण का अनुसरण करता है। यथार्थवाद मानता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था असुरक्षित और अराजक है, जहाँ प्रत्येक राज्य को अपनी रक्षा हेतु शक्ति का सहारा लेना पड़ता है। इस विचारधारा में आदर्शों के स्थान पर व्यावहारिक हितों और राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोपरि माना जाता है। शक्ति ही वह प्राथमिक माध्यम है जिसके द्वारा राज्य एक प्रतिस्पर्धी और अनिश्चित वैश्विक वातावरण में अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं।

25. (C) शक्ति की सीमा : निरंतर शस्त्रों की दौड़
शक्ति की सीमा का अर्थ उन कारकों से है जो किसी राज्य की शक्ति के प्रयोग को नियंत्रित करते हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय कानून या अन्य राज्यों का विरोध। निरंतर शस्त्रों की दौड़ शक्ति की सीमा नहीं, बल्कि यह शक्ति बढ़ाने की एक प्रक्रिया है जो असुरक्षा को बढ़ाती है। सैन्य उपकरण मूर्त शक्ति के उदाहरण हैं और राष्ट्रीय मनोबल अमूर्त तत्व है। बल प्रयोग शक्ति के प्रदर्शन का एक तरीका है। अतः शस्त्रों की दौड़ को शक्ति की सीमा मानना वैचारिक रूप से गलत युग्म है।

26. (A) राष्ट्रीय हित
जब कोई सरकार अपनी विदेश नीति में ऊर्जा सुरक्षा और तेल भंडारों तक पहुंच सुनिश्चित करने को प्राथमिकता देती है, तो वह अपने राष्ट्रीय हित की दिशा में कार्य कर रही होती है। राष्ट्रीय हित में वे सभी आर्थिक और सुरक्षा संबंधी लक्ष्य शामिल होते हैं जो देश के कल्याण हेतु अनिवार्य हैं। संसाधनों की प्राप्ति राष्ट्र की शक्ति बढ़ाती है और भविष्य की चुनौतियों से निपटने की क्षमता प्रदान करती है। यह व्यवहार दर्शाता है कि विदेश नीति अनिवार्य रूप से राष्ट्र की बुनियादी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाई जाती है।

27. (D) राजनीतिक सिद्धांत बनाने वाले विचारों और मूल्यों का एक व्यवस्थित निकाय।
अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विचारधारा विचारों, विश्वासों और मूल्यों के उस व्यवस्थित समूह को संदर्भित करती है जो राजनीतिक व्यवस्था का आधार बनते हैं। यह न केवल घरेलू नीतियों को दिशा देती है, बल्कि किसी देश के बाहरी संबंधों और विश्व के प्रति उसके दृष्टिकोण को भी प्रभावित करती है। शीतयुद्ध जैसे संघर्षों में विचारधारा ने शत्रु और मित्र की पहचान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह राज्यों के कार्यों को वैध बनाने और उनके वैश्विक लक्ष्यों को परिभाषित करने हेतु एक वैचारिक ढांचा प्रदान करती है।

NODIA

80. (A) केवल 1 और 2
शक्ति एक अत्यंत जटिल अवधारणा है जिसमें सैन्य क्षमता के साथ-साथ आर्थिक प्रभाव और सांस्कृतिक आकर्षण भी शामिल हैं। कथन 2 सही है क्योंकि केवल संसाधनों का होना पर्याप्त नहीं है, उनका कुशलतापूर्वक उपयोग करने की क्षमता ही वास्तविक प्रभाव पैदा करती है। कथन 3 गलत है क्योंकि शक्ति केवल परमाणु हथियारों तक सीमित नहीं है; कई गैर-परमाणु संपन्न राष्ट्र भी आर्थिक रूप से बहुत शक्तिशाली हो सकते हैं। अतः शक्ति को समग्र रूप से संसाधनों, उनके प्रबंधन और उनके द्वारा उत्पन्न वैश्विक प्रभाव के संगम के रूप में देखना चाहिए जो व्यापक होता है।

81. (A) लक्ष्यों की पहचान करने की प्रक्रिया और फिर उन्हें प्राप्त करने के लिए कूटनीति जैसे उपकरणों का उपयोग करना।
राष्ट्रीय हित को बढ़ावा देना एक सुनियोजित रणनीतिक प्रक्रिया है जिसमें सबसे पहले देश की सुरक्षा और समृद्धि के उद्देश्यों को पहचाना जाता है। इसके बाद, इन लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु कूटनीति, आर्थिक संबंधों और सैन्य शक्ति का उपयोग किया जाता है। यह प्रक्रिया अन्य राष्ट्रों के हितों और वैश्विक वातावरण को ध्यान में रखकर संचालित की जाती है। यह किसी एक व्यक्ति का कार्य नहीं है, बल्कि राष्ट्र की दीर्घकालिक आवश्यकताओं और अंतर्राष्ट्रीय वास्तविकताओं के बीच संतुलन बिठाने का एक निरंतर कूटनीतिक और रणनीतिक प्रयास है।

82. (D) मानवाधिकारों और शासन के स्वरूपों पर विवादों में।
यद्यपि शीतयुद्ध की समाप्ति के बाद पुरानी वैचारिक प्रतिस्पर्धा कुछ कम हुई है, फिर भी विचारधारा आज भी अंतर्राष्ट्रीय विवादों के केंद्र में मौजूद है। यह तब दिखाई देता है जब विभिन्न राष्ट्र शासन के तरीकों (जैसे लोकतंत्र बनाम निरंकुशता) या मानवाधिकारों की व्याख्या को लेकर एक-दूसरे की आलोचना करते हैं। ये विवाद अक्सर गहरे वैचारिक मतभेदों से उपजे होते हैं जो यह तय करते हैं कि समाज को कैसे संगठित किया जाना चाहिए। अतः विचारधारा आज भी कूटनीतिक संबंधों और वैश्विक गठबंधनों को प्रभावित करने वाला एक अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व बनी हुई है।

83. (C) राजनीतिक या भू-राजनीतिक कारण
युद्ध के राजनीतिक या भू-राजनीतिक कारणों का संबंध सीधे तौर पर भूमि, प्राकृतिक संसाधनों या रणनीतिक क्षेत्रों पर नियंत्रण से होता है। जब दो राष्ट्र एक ही भूभाग पर अपना दावा करते हैं या ऊर्जा संसाधनों हेतु प्रतिस्पर्धा करते हैं, तो तनाव बढ़ता है जो अक्सर सशस्त्र संघर्ष में बदल जाता है। यह शक्ति के विस्तार और भौगोलिक प्रभुत्व की इच्छा से प्रेरित होता है। ऐसे युद्धों का मुख्य उद्देश्य अपने राज्य की भौतिक सीमाओं और आर्थिक आधार को मजबूत करना होता है, जो इसे वैचारिक या जातीय युद्धों से अलग भौगोलिक आधार प्रदान करता है।

84. (A) परमाणु निवारण सिद्धांत
'परस्पर सुनिश्चित विनाश' परमाणु निवारण का वह कठोर सिद्धांत है जो मानता है कि यदि दो परमाणु संपन्न राष्ट्रों के बीच युद्ध होता है, तो दोनों ही पक्ष पूरी तरह नष्ट हो जाएंगे। इस स्थिति में कोई विजेता नहीं होगा, केवल सर्वनाश होगा। यही विनाशकारी परिणाम का भय दोनों पक्षों को आक्रमण करने से रोकता है। यह सिद्धांत शीतयुद्ध के दौरान वैश्विक शांति का एक अनूठा आधार बना रहा। यह इस तर्क पर आधारित है कि हथियारों की अत्यधिक विनाशकता ही अंततः युद्ध को रोकने का सबसे बड़ा कारण बन जाती है, जो रणनीतिक स्थिरता है।

85. (D) अनुसमर्थन और प्रवर्तन की प्रक्रिया
संधि कानून के अंतर्गत किसी समझौते का वास्तविक प्रभाव तभी शुरू होता है जब संबंधित राज्य औपचारिक रूप से उसका अनुसमर्थन करते हैं और उसे लागू करने हेतु कदम उठाते हैं। अनुसमर्थन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक राज्य अपनी सहमति की पुष्टि करता है कि वह संधि की शर्तों से कानूनी रूप से बंधा हुआ है। इसके बाद प्रवर्तन तंत्र यह सुनिश्चित करता है कि संधि के प्रावधानों का पालन हो। यह विधिक ढांचा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए गए वादों को केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहने देता, बल्कि उन्हें सक्रिय और बाध्यकारी दायित्वों में बदल देता है।

86. (B) अपने अंतर्राष्ट्रीय कानूनी दायित्वों का पालन करना।
अंतर्राष्ट्रीय कानून में राज्यों को न केवल अधिकार प्राप्त हैं, बल्कि उनके कुछ अनिवार्य कर्तव्य भी हैं। इनमें सबसे प्रमुख कर्तव्य उन संधियों और कानूनी नियमों का पालन करना है जिन पर उन्होंने सहमति दी है। यह कर्तव्य 'पाक्टा संट सरवेंडा' के सिद्धांत पर आधारित है, जो वैश्विक व्यवस्था में स्थिरता लाता है। यदि राज्य अपने दायित्वों से पीछे हटते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और शांति का पूरा ढांचा ढह सकता है। इसलिए, संप्रभु होने के बावजूद, राज्यों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे वैश्विक समुदाय के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में कार्य करें।

87. (C) पूर्वी यूरोप में साम्यवादी शासन का पतन और सोवियत संघ का विघटन।
शीतयुद्ध की समाप्ति का सबसे निर्णायक क्षण 1980 के दशक के उत्तरार्ध में पूर्वी यूरोप में हुए लोकतांत्रिक परिवर्तनों और 1991 में सोवियत संघ के आधिकारिक विघटन के रूप में आया। इसने न केवल एक महाशक्ति का अंत किया, बल्कि साम्यवादी विचारधारा के प्रभुत्व को भी गहरा झटका दिया। बर्लिन की दीवार का गिरना और जर्मनी का पुनर्मिलन इस युग के अंत के प्रतीक बने। इस घटना ने द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था को समाप्त कर दिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में एक नए वैश्विक परिदृश्य की शुरुआत की, जिसने पूरी दुनिया की राजनीति बदल दी।

88. (D) अधिनिर्णय
अधिनिर्णय विवादों के समाधान की वह विधिक पद्धति है जिसमें विवादित पक्ष अपने मामले को किसी अंतर्राष्ट्रीय अदालत या स्वतंत्र न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। इसमें न्यायाधिकरण दोनों पक्षों के तर्कों और साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद एक अंतिम निर्णय देता है जो दोनों पक्षों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होता है। यह वार्ता या मध्यस्थता से भिन्न है क्योंकि यहाँ निर्णय लेने की शक्ति पक्षों के हाथ में नहीं, बल्कि एक तटस्थ न्यायिक निकाय के पास होती है। यह

Downloaded from www.pdf.tube

37. (D) जैव-रासायनिक युद्ध
जब किसी संघर्ष में घातक जैविक एजेंटों जैसे बैक्टीरिया, वायरस या जहरीले रसायनों का उपयोग किया जाता है, तो उसे जैव-रासायनिक युद्ध कहा जाता है। ये सामूहिक विनाश के हथियार माने जाते हैं क्योंकि ये बहुत कम मात्रा में भी व्यापक जनहानि करने और पर्यावरण को दीर्घकालिक नुकसान पहुँचाने की क्षमता रखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इनके भयानक मानवीय परिणामों को देखते हुए संधियों के माध्यम से इनके उपयोग पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। यह युद्ध के सबसे अमानवीय और खतरनाक स्वरूपों में से एक है, जो मानवता के लिए गंभीर खतरा है।

38. (A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
वैश्वीकरण ने राष्ट्र-राज्यों के पारंपरिक संप्रभु अधिकारों को गहराई से प्रभावित किया है। आर्थिक निवेश और सूचना प्रौद्योगिकी के प्रवाह ने राज्य की सीमाओं को पारगम्य बना दिया है। इसके अतिरिक्त, वैश्विक संस्थान और कानून राज्यों को कुछ मानकों का पालन करने हेतु बाध्य करते हैं, जिससे उनके घरेलू नीतियों पर नियंत्रण कम होता है। यह परस्पर संबद्धता राज्यों को बाहरी प्रभावों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाती है और उनकी स्वायत्त निर्णय लेने की शक्ति को सीमित करती है। अतः कारण अभिकथन की सटीक व्याख्या करता है कि वैश्वीकरण संप्रभुता को प्रभावित कर रहा है।

39. (C) शस्त्र नियंत्रण हथियारों के प्रबंधन पर केंद्रित है, जबकि निरस्त्रीकरण का उद्देश्य उन्हें कम करना या समाप्त करना है।
शस्त्र नियंत्रण और निरस्त्रीकरण दोनों शांति बनाए रखने के साधन हैं, लेकिन उनके दृष्टिकोण भिन्न हैं। शस्त्र नियंत्रण का उद्देश्य हथियारों की प्रतिस्पर्धा को विनियमित करना और आकस्मिक युद्ध के जोखिम को कम करना है। दूसरी ओर, निरस्त्रीकरण अधिक व्यापक लक्ष्य है जो हथियारों के भंडार को कम करने या उन्हें पूरी तरह समाप्त करने पर बल देता है। सरल शब्दों में, शस्त्र नियंत्रण हथियारों के कुशल 'प्रबंधन' की बात करता है, जबकि निरस्त्रीकरण हथियारों के 'उन्मूलन' या प्रभावी कटौती का दीर्घकालिक लक्ष्य रखता है ताकि सैन्यीकरण कम हो सके।

40. (A) मानव प्रकृति मौलिक रूप से अच्छी है और सहयोग करने में सक्षम है।
आदर्शवादी दृष्टिकोण का मूल आधार मानव प्रकृति के प्रति एक आशावादी दृष्टि है। यह मानता है कि मनुष्य स्वभाव से तर्कसंगत है और शांतिपूर्ण सहयोग की ओर प्रवृत्त होता है। आदर्शवादियों के अनुसार, संघर्ष और युद्ध मानव स्वभाव की नहीं, बल्कि दोषपूर्ण राजनीतिक व्यवस्थाओं की उपज हैं। यदि उपयुक्त अंतर्राष्ट्रीय कानून और लोकतांत्रिक संस्थान बनाए जाएं, तो मानव प्रकृति की अच्छाई का उपयोग एक न्यायपूर्ण और युद्धमुक्त विश्व बनाने के लिए किया जा सकता है। यह दृष्टिकोण संघर्ष के बजाय सहयोग को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सामान्य नियम मानता है।

41. (C) शीतयुद्ध
शीतयुद्ध काल की सबसे प्रमुख पहचान सैन्य गठबंधनों का निर्माण था, जिसमें नाटो पश्चिमी गुट का और वारसॉ पैक्ट पूर्वी गुट का प्रतिनिधित्व करता था। ये गठबंधन सामूहिक रक्षा के सिद्धांत पर आधारित थे, जहाँ एक सदस्य पर हमले को सभी पर हमला माना जाता था। इस काल में वैश्विक राजनीति पूरी तरह इन दो प्रतिस्पर्धी सैन्य ढांचों के बीच शक्ति संतुलन पर आधारित थी। इसने दुनिया को दो स्पष्ट गुटों में विभाजित कर दिया और प्रत्यक्ष संघर्ष की निरंतर संभावना बनी रही, जिससे वैश्विक तनाव में वृद्धि हुई।

42. (A) दूसरों के व्यवहार को प्रभावित करने की राज्य की क्षमता।
अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति को एक ऐसी क्षमता के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके द्वारा एक राज्य अन्य राज्यों के कार्यों या नीतियों को अपने अनुकूल मोड़ने में सफल होता है। यह केवल सैन्य बल तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें आर्थिक प्रभाव और कूटनीतिक कौशल भी शामिल हैं। शक्ति एक संबंधात्मक अवधारणा है, जिसका अर्थ है कि यह दूसरे देशों के संदर्भ में ही प्रभावी होती है। वास्तव में, शक्ति वह साधन है जिसके माध्यम से राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने और वैश्विक व्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं।

43. (D) राजनीतिक नेतृत्व की गुणवत्ता
राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों को मूर्त और अमूर्त श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। सशस्त्र बल और प्राकृतिक संसाधन मूर्त तत्व हैं क्योंकि उन्हें मापा जा सकता है। इसके विपरीत, राजनीतिक नेतृत्व की गुणवत्ता, राष्ट्रीय मनोबल और कूटनीतिक चातुर्य अमूर्त तत्व हैं जिन्हें सीधे मापा नहीं जा सकता, परंतु वे राष्ट्र की सफलता में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। एक कुशल नेतृत्व उपलब्ध भौतिक संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग कर देश के प्रभाव को वैश्विक मंच पर बढ़ा सकता है। अतः यह शक्ति का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अदृश्य स्तंभ माना जाता है।

44. (B) P-2, Q-1, R-4, S-3
निरस्त्रीकरण का संबंध हथियारों की कटौती से है, जबकि निवारण का अर्थ शत्रु को प्रतिशोध की धमकी देकर हमला करने से रोकना है। कूटनीति वह माध्यम है जिसके द्वारा राज्य अपने आधिकारिक प्रतिनिधियों के जरिए आपसी संबंधों का संचालन करते हैं। हस्तक्षेप का तात्पर्य किसी अन्य राज्य के आंतरिक मामलों में बलपूर्वक और अनपेक्षित प्रवेश से है। ये सभी अवधारणाएं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट करती हैं, जो शांति स्थापना से लेकर शक्ति के प्रयोग और कूटनीतिक संवाद तक विस्तृत हैं। ये राष्ट्रों के व्यवहार को दिशा प्रदान करते हैं।

45. (C) वैश्विक शक्ति संतुलन में एक मौलिक बदलाव।
शीतयुद्ध के समापन के साथ ही दशकों से चली आ रही द्विध्रुवीय व्यवस्था का अंत हो गया, जिसने वैश्विक शक्ति संतुलन को पूरी तरह बदल दिया। सोवियत संघ के विघटन के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका एकमात्र महाशक्ति के रूप में उभरा और विश्व राजनीति एकध्रुवीयता की ओर बढ़ी। इसके साथ ही साम्यवाद बनाम पूंजीवाद का वैचारिक संघर्ष भी समाप्त

कम करने हेतु कूटनीति का एक अत्यंत प्रभावी उपकरण है, जो शांति सुनिश्चित करती है।

63. (D) कथन I असत्य है, लेकिन कथन II सत्य है।
गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य कोई नया सैन्य गुट बनाना नहीं था, बल्कि महाशक्तियों की सैन्य प्रतिस्पर्धा से दूर रहना था। यह नीति नव-स्वतंत्र राष्ट्रों को अपनी संप्रभुता सुरक्षित रखने और शीतयुद्ध के तनावों से बचने हेतु एक मंच प्रदान करती थी। गुटनिरपेक्षता का अर्थ है किसी भी शक्ति गुट के साथ औपचारिक सैन्य गठबंधन में शामिल न होकर गुण-दोष के आधार पर स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन करना। यह आंदोलन वैश्विक शांति, उपनिवेशवाद के विरोध और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने हेतु प्रतिबद्ध था, न कि सैन्य शक्ति के संचय के लिए।

64. (D) एक द्विपक्षीय संधि में दो राज्य शामिल होते हैं, जबकि एक बहुपक्षीय संधि में दो से अधिक राज्य शामिल होते हैं।
संधियों का वर्गीकरण मुख्य रूप से उनमें शामिल होने वाले पक्षों की संख्या के आधार पर किया जाता है। द्विपक्षीय संधि दो राष्ट्रों के बीच किसी विशिष्ट मुद्दे, जैसे व्यापार, को हल करने के लिए होती है। इसके विपरीत, बहुपक्षीय संधि में तीन या अधिक देश शामिल होते हैं और यह अक्सर जलवायु परिवर्तन या मानवाधिकार जैसे वैश्विक महत्व के विषयों को संबोधित करती है। दोनों ही प्रकार की संधियाँ अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत समान रूप से बाध्यकारी होती हैं और राज्यों के बीच सहयोग का ढांचा तैयार करती हैं, जिससे वैश्विक व्यवस्था स्थिर होती है।

65. (A) शस्त्रों की दौड़
जब कोई देश अपने प्रतिद्वंद्वी की तुलना में सैन्य बढ़त हासिल करने हेतु लगातार हथियारों का संचय करता है, तो यह स्थिति 'शस्त्रों की दौड़' कहलाती है। यह प्रतिस्पर्धा अविश्वास और असुरक्षा की भावना से प्रेरित होती है, जहाँ एक पक्ष की सैन्य वृद्धि दूसरे पक्ष को और अधिक शक्तिशाली बनने हेतु प्रेरित करती है। यह प्रक्रिया अंततः हथियारों के भंडार में भारी वृद्धि और क्षेत्रीय अस्थिरता की ओर ले जाती है। यह निवारण का एक जोखिम भरा रूप है जो तनाव कम करने के बजाय उसे बढ़ा देता है और वैश्विक शांति के समक्ष चुनौती उत्पन्न करता है।

66. (B) अंतर्राष्ट्रीय कानून और संगठनों का विकास।
युद्ध की रोकथाम और उसके पूर्ण उन्मूलन का लक्ष्य आदर्शवादी विचारधारा का केंद्र है, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून और संस्थानों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र जैसे संगठनों की स्थापना इसी उद्देश्य से की गई थी कि राष्ट्रों के बीच विवादों का समाधान बल प्रयोग के बजाय कूटनीतिक तरीकों से हो। यह अवधारणा मानती है कि यदि राज्यों का व्यवहार नियमों और सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था से नियंत्रित हो, तो युद्ध की आवश्यकता को समाप्त किया जा सकता है। यह शक्ति की राजनीति के स्थान पर वैश्विक न्याय और व्यवस्था पर बल देता है।

67. (C) नई वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों का उदय।
शीतयुद्ध की समाप्ति ने यद्यपि महाशक्तियों के बीच परमाणु युद्ध के खतरे को कम किया, लेकिन इसने नई और जटिल सुरक्षा चुनौतियों को जन्म दिया। द्विध्रुवीय स्थिरता के हटने से कई क्षेत्रों में दबे हुए जातीय विवाद और उग्र राष्ट्रवाद उभरकर सामने आए। इसके अतिरिक्त, आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन और साइबर सुरक्षा जैसे गैर-पारंपरिक खतरे वैश्विक राजनीति के केंद्र में आ गए। आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय संबंध अब केवल राज्यों के बीच के युद्धों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे इन बहुआयामी और सीमा-पार चुनौतियों से निपटने की रणनीतियों पर अधिक केंद्रित हो गए हैं।

68. (A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
आदर्शवादी विचारक इस बात पर जोर देते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को अराजकता से बाहर निकालने के लिए मजबूत संस्थागत ढांचे की आवश्यकता है। उनका तर्क है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और संगठन राज्यों के व्यवहार को विनियमित कर सकते हैं और उनमें आपसी विश्वास पैदा कर सकते हैं। जब राज्य साझा नियमों और मंचों के माध्यम से बातचीत करते हैं, तो सहयोग की संभावना बढ़ जाती है और संघर्ष की आशंका कम होती है। यह विश्वास कि संस्थाएं मानवीय विवेक का विस्तार हैं, आदर्शवाद का मूल आधार है जो कारण को अभिकथन के साथ जोड़ता है।

69. (A) कुशल वार्ता, संचार और सामान्य आधार खोजने की इच्छा।
कूटनीति की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वार्ताकार कितने प्रभावी ढंग से संवाद करते हैं और मतभेदों के बीच सहमति के बिंदुओं को कैसे तलाशते हैं। इसमें धैर्य, रणनीतिक सोच और एक-दूसरे के हितों के प्रति सम्मान आवश्यक है। कूटनीति बल प्रयोग का विकल्प है, इसलिए इसमें समझौता करने की लचीली मानसिकता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब राज्य अपनी कठोर मांगों से पीछे हटने और सामूहिक लाभ हेतु काम करने को तैयार होते हैं, तभी कूटनीतिक सफलता प्राप्त होती है। यह राष्ट्रों के बीच शत्रुता को शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व में बदलती है।

70. (D) बलपूर्वक अन्य राष्ट्रों पर अपनी विचारधारा थोपने का अधिकार
अंतर्राष्ट्रीय कानून राज्यों को संप्रभुता, समानता और क्षेत्रीय अखंडता जैसे अधिकार प्रदान करता है, लेकिन वह किसी देश को दूसरों पर अपनी विचारधारा थोपने का अधिकार नहीं देता। ऐसा करना संप्रभुता और गैर-हस्तक्षेप के मौलिक सिद्धांतों का उल्लंघन है। प्रत्येक राष्ट्र को अपनी राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था चुनने की पूर्ण स्वतंत्रता है। बल प्रयोग के माध्यम से वैचारिक प्रसार अवैध है और अंतर्राष्ट्रीय अशांति का प्रमुख कारण बनता है। कानून का उद्देश्य राज्यों के बीच विविधता और स्वतंत्रता का सम्मान करना है ताकि वैश्विक शांति सुनिश्चित की जा सके।

71. (B) मूर्त और मापने योग्य
किसी राज्य की शक्ति के उन तत्वों को मूर्त कहा जाता है जिन्हें भौतिक रूप से देखा या मापा जा सकता है। इसमें देश का कुल

Click Here to Buy book on Amazon

तक जारी रहा। इस दौरान दोनों पक्षों ने सैन्य गठबंधनों का निर्माण किया और विकासशील देशों में अपने प्रभाव हेतु परोक्ष युद्धों में भाग लिया। यह एक ऐसी व्यवस्था थी जहाँ दुनिया परमाणु युद्ध के साये में जी रही थी और कूटनीति पूरी तरह वैचारिक शत्रुता से प्रभावित थी, जिससे वैश्विक स्थिरता खंडित थी।

55. (C) खेल सिद्धांत : रणनीतिक स्थितियों में तर्कसंगत निर्णय लेने पर ध्यान
खेल सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का वह विश्लेषण है जो मानता है कि राज्य तर्कसंगत अभिनेता हैं जो प्रतिस्पर्धी स्थितियों में अपने लाभ को अधिकतम करने का प्रयास करते हैं। यह विभिन्न मॉडलों के माध्यम से दर्शाता है कि कैसे एक पक्ष का निर्णय दूसरे पक्ष की प्रतिक्रिया को प्रभावित करता है। विकल्प A गलत है क्योंकि आदर्शवाद सहयोग पर ध्यान देता है, B गलत है क्योंकि यथार्थवाद शक्ति पर केंद्रित है, और D गलत है क्योंकि व्यवस्था सिद्धांत संरचना पर ध्यान देता है। अतः खेल सिद्धांत ही रणनीतिक निर्णयों के वैज्ञानिक विश्लेषण हेतु सही रूप से पहचाना जाता है।

56. (A) नौकरशाही राजनीति मॉडल
नौकरशाही राजनीति मॉडल यह तर्क देता है कि किसी देश की विदेश नीति किसी एक व्यक्ति का तर्कसंगत निर्णय नहीं होती, बल्कि यह सरकारी मंत्रालयों और एजेंसियों के बीच होने वाली सौदेबाजी का परिणाम है। प्रत्येक विभाग (जैसे रक्षा या विदेश मंत्रालय) के अपने स्वार्थ और दृष्टिकोण होते हैं, और अंतिम निर्णय अक्सर इन प्रतिस्पर्धी हितों के बीच एक समझौते के रूप में उभरता है। यह मॉडल राज्य को एक एकात्मक अभिनेता मानने के बजाय उसे आंतरिक रूप से खंडित और जटिल प्रक्रिया के रूप में देखता है जहाँ नीति निर्माण एक आंतरिक सत्ता संघर्ष है।

57. (D) किसी सामान्य खतरे के विरुद्ध सामूहिक सुरक्षा या शक्ति को बढ़ाना।
अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में गठबंधन मुख्य रूप से राज्यों के बीच रक्षात्मक या आक्रामक सहयोग के उद्देश्य से बनाए जाते हैं। जब कई राज्य महसूस करते हैं कि वे अकेले किसी शक्तिशाली शत्रु का सामना नहीं कर सकते, तो वे अपनी क्षमताओं को मिलाकर एक गठबंधन बनाते हैं। यह शक्ति संतुलन बनाए रखने का एक प्रमुख रणनीतिक साधन है। गठबंधन के सदस्य एक-दूसरे की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध होते हैं, जिससे संभावित हमलावर के लिए युद्ध की लागत बढ़ जाती है। यह किसी भी राष्ट्र की व्यक्तिगत कमजोरी को सामूहिक शक्ति में बदलने की एक प्रक्रिया है।

58. (A) अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की अराजक संरचना और उससे उत्पन्न सुरक्षा दुविधा।
यथार्थवादी परिप्रेक्ष्य में, शस्त्रों की दौड़ का मूल कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की वह बनावट है जहाँ राज्यों के ऊपर कोई सर्वोच्च सत्ता नहीं है। इस अराजक स्थिति में प्रत्येक राज्य अपनी सुरक्षा के लिए स्वयं जिम्मेदार होता है। जब एक राज्य सैन्य शक्ति बढ़ाता है, तो पड़ोसी राज्य उसे खतरे के रूप में देखते हैं और वे भी जवाबी कार्रवाई में हथियार जुटाना शुरु कर देते हैं। इस सुरक्षा दुविधा के कारण शस्त्रों का एक ऐसा प्रतिस्पर्धी चक्र शुरु होता है जिसका कोई तार्किक अंत नहीं होता। यह विश्वास की कमी का सीधा परिणाम है।

59. (C) संप्रभुता
अंतर्राष्ट्रीय कानून में हस्तक्षेप को सामान्यतः किसी राज्य की संप्रभुता का उल्लंघन माना जाता है क्योंकि संप्रभुता का अर्थ है अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में पूर्ण स्वतंत्रता। जब कोई बाहरी शक्ति बलपूर्वक किसी देश के निर्णयों को प्रभावित करती है, तो वह उस राष्ट्र के संप्रभु अधिकार को चुनौती देती है। गैर-हस्तक्षेप का सिद्धांत राज्यों के बीच शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की एक अनिवार्य शर्त है। केवल असाधारण परिस्थितियों (जैसे नरसंहार) में ही हस्तक्षेप को कुछ हद तक मान्यता प्राप्त है, अन्यथा यह संप्रभुता का गंभीर हनन है जो वैश्विक शांति को बाधित करता है।

60. (A) एक शक्तिशाली विरोधी गठबंधन का अस्तित्व।
किसी भी राज्य की शक्ति पूर्णतः असीमित नहीं होती और वह बाहरी बाधाओं से सीमित होती है। एक शक्तिशाली विरोधी गठबंधन का होना राज्य की कार्य करने की स्वतंत्रता और उसके प्रभाव को सीधे तौर पर चुनौती देता है। जब अन्य राष्ट्र एकजुट होकर किसी देश की आक्रामक नीतियों का विरोध करते हैं, तो उस देश के लिए अपनी इच्छा थोपना कठिन हो जाता है। यह शक्ति संतुलन की राजनीति का हिस्सा है। अन्य विकल्प जैसे बड़ी सेना या बढ़ती अर्थव्यवस्था वास्तव में शक्ति बढ़ाने वाले कारक हैं, न कि उसकी सीमाओं के उदाहरण, जो प्रभाव को बढ़ाते हैं।

61. (D) आधुनिक युग में राष्ट्रीय हित के निर्धारण में विचारधारा की कोई भूमिका नहीं है।
विचारधारा आज भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और यह कहना गलत होगा कि आधुनिक युग में इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। यद्यपि शीतयुद्ध की समाप्ति के बाद वैचारिक तीव्रता कम हुई है, फिर भी मानवाधिकारों और लोकतंत्र जैसे विषयों पर विचारधाराएं आज भी राष्ट्रों के बीच सहयोग और विवाद का आधार बनती हैं। विचारधारा विदेश नीति को एक नैतिक ढांचा प्रदान करती है और राज्यों को वैश्विक मंच पर अपनी पहचान बनाने में सहायता करती है। सैन्य शक्ति और अर्थव्यवस्था के साथ मिलकर यह राष्ट्रीय शक्ति को सुदृढ़ करती है।

62. (B) मध्यस्थता
मध्यस्थता विवाद निपटान की एक ऐसी शांतिपूर्ण विधि है जिसमें एक निष्पक्ष तीसरा पक्ष शामिल होकर विवादित राष्ट्रों के बीच समाधान खोजने में मदद करता है। मध्यस्थ का कार्य दोनों पक्षों की बात सुनना, उनके बीच की गलतफहमी दूर करना और एक स्वीकार्य प्रस्ताव प्रस्तुत करना होता है जिससे संघर्ष टल सके। यह साधारण वार्ता से एक कदम आगे है क्योंकि इसमें बाहरी हस्तक्षेप सकारात्मक रूप से शामिल होता है। यह प्रक्रिया रक्तपात को रोकने और राज्यों के बीच तनाव

NODIA

प्रभाव राष्ट्र की एकता और कूटनीतिक प्रभाव को बढ़ाता है, जबकि सैन्य शक्ति और अर्थव्यवस्था प्रत्यक्ष रूप से शक्ति में वृद्धि करते हैं।

10. (A) सूचना प्रवाह और धारणा की विशिष्ट प्रक्रियाएं।
अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संचार दृष्टिकोण इस विचार पर आधारित है कि राज्यों के बीच अंतःक्रियाएं सूचनाओं के आदान-प्रदान पर निर्भर करती हैं। यह दृष्टिकोण साइबरनेटिक्स के सिद्धांतों का उपयोग करके समझता है कि कैसे संदेशों का प्रवाह, प्राप्तकर्ता की धारणाएं और प्रतिपुष्टि प्रणालियाँ अंतर्राष्ट्रीय निर्णयों को आकार देती हैं। सूचना की सटीकता या त्रुटियां ही राष्ट्रों के बीच सहयोग या संघर्ष का कारण बनती हैं। यह वैश्विक व्यवस्था को सूचना प्रसंस्करण के एक जटिल जाल के रूप में देखता है।

11. (D) राष्ट्रीय हित को आकार देने और उसे उचित ठहराने में विचारधारा की भूमिका।
विचारधारा अक्सर राष्ट्रों की विदेश नीति के उद्देश्यों को वैधानिक आधार प्रदान करती है। जब कोई राज्य अपनी विस्तारवादी नीतियों को किसी विशिष्ट राजनीतिक या सामाजिक व्यवस्था के प्रसार के रूप में प्रस्तुत करता है, तो वह अपनी महत्वाकांक्षाओं को नैतिक आवरण पहना रहा होता है। यह प्रक्रिया जनता का समर्थन प्राप्त करने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यों को न्यायसंगत सिद्ध करने में सहायक होती है। विचारधारा यहाँ राष्ट्रीय हितों को परिभाषित करने और उन्हें प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है।

12. (B) जातीय विवाद
जब संघर्ष का मूल कारण भाषा, संस्कृति, धर्म या साझा ऐतिहासिक पहचान से जुड़ी स्वायत्तता की मांग होती है, तो इसे जातीय विवाद कहते हैं। ऐसे विवाद अक्सर राष्ट्र-राज्यों की सीमाओं के भीतर पहचान के संकट से उत्पन्न होते हैं। ये संघर्ष केवल भौतिक संसाधनों के लिए नहीं, बल्कि अपनी विशिष्ट पहचान और सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए लड़े जाते हैं। आधुनिक विश्व में इस प्रकार के संघर्षों ने वैश्विक सुरक्षा और स्थिरता के समक्ष गंभीर चुनौतियाँ उत्पन्न की हैं।

13. (C) अस्वीकार्य प्रतिशोधात्मक क्षति पहुँचाने की क्षमता बनाए रखकर हमलों को रोकना।
परमाणु निवारण का सिद्धांत इस धारणा पर आधारित है कि यदि शत्रु देश जानता है कि आक्रमण की स्थिति में उसे विनाशकारी प्रतिशोध झेलना पड़ेगा, तो वह हमला नहीं करेगा। इसका उद्देश्य युद्ध जीतना नहीं, बल्कि युद्ध को होने से रोकना है। यह 'परस्पर सुनिश्चित विनाश' की संभावना पैदा करता है जहाँ दोनों पक्ष जानते हैं कि परमाणु संघर्ष में कोई विजेता नहीं होगा। यह भय पर आधारित शांति की एक रणनीतिक स्थिति है जो वैश्विक स्थिरता बनाए रखती है।

14. (A) P-3, Q-1, R-4, S-2
यथार्थवादी दृष्टिकोण का मुख्य फोकस शक्ति और राष्ट्रीय हित पर होता है, जबकि आदर्शवादी दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय कानून और नैतिकता को महत्व देता है। खेल सिद्धांत रणनीतिक अंतःक्रियाओं और अधिकतम लाभ प्राप्त करने के मॉडलों का विश्लेषण करता है। निर्णय-प्रक्रिया दृष्टिकोण में नौकरशाही राजनीति और व्यक्तियों के मनोवैज्ञानिक कारकों का अध्ययन किया जाता है। ये चारों सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने के अलग-अलग आयाम प्रस्तुत करते हैं, जो क्रमशः शक्ति, मूल्य, तर्कसंगत विकल्प और आंतरिक प्रक्रियाओं पर आधारित विश्लेषण प्रदान करते हैं।

15. (A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।
शस्त्रों की दौड़ राज्यों के बीच हथियारों की गुणवत्ता और मात्रा में निरंतर वृद्धि की एक प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया है। यह अक्सर सुरक्षा दुविधा से उत्पन्न होती है, जहाँ एक देश द्वारा अपनी सुरक्षा हेतु उठाए गए कदम दूसरे देश में असुरक्षा पैदा करते हैं। इसके परिणामस्वरूप दूसरा देश भी अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाता है, जिससे असुरक्षा का एक अंतहीन चक्र शुरू हो जाता है। यह स्थिति न केवल आर्थिक संसाधनों पर बोझ डालती है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय तनाव और युद्ध की संभावना बढ़ाती है।

16. (B) राजनयिक वार्ता
राजनयिक वार्ता अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने का सबसे प्राथमिक और शांतिपूर्ण साधन है। इसमें राष्ट्रों के प्रतिनिधि प्रत्यक्ष बातचीत के माध्यम से मतभेदों को हल करने और सहमति पर पहुँचने का प्रयास करते हैं। सैन्य हस्तक्षेप, आर्थिक प्रतिबंध और शस्त्रों की दौड़ अक्सर तनाव बढ़ाते हैं, जबकि वार्ता कूटनीति का उपयोग कर रक्तपात को टालती है। यह प्रक्रिया आपसी समझ, विश्वास निर्माण और अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। शांतिपूर्ण समाधान हेतु यह सबसे प्रभावी कूटनीतिक विकल्प माना जाता है।

17. (B) दो महाशक्ति-नेतृत्व वाले वैचारिक गुटों के बीच एक द्विध्रुवीय टकराव।
शीतयुद्ध काल द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की वह अवधि थी जिसमें विश्व संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के नेतृत्व वाले दो स्पष्ट गुटों में विभाजित हो गया था। यह केवल सैन्य प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि पूंजीवाद और साम्यवाद जैसी विरोधी विचारधाराओं के बीच गहरा संघर्ष था। इस द्विध्रुवीय व्यवस्था में प्रत्यक्ष युद्ध के स्थान पर परोक्ष युद्ध, जासूसी और शस्त्रों की दौड़ प्रमुख थी। वैश्विक राजनीति पूरी तरह इन दो ध्रुवों के बीच शक्ति संतुलन की रणनीतियों से प्रभावित रही।

18. (A) किसी भी प्रमुख शक्ति गुट के साथ या उसके विरुद्ध औपचारिक रूप से शामिल होने से इनकार करना।
गुटनिरपेक्षता का मूल सिद्धांत शीतयुद्ध के दौरान उभरे दोनों महाशक्ति गुटों से स्वतंत्र रहने की नीति है। इसका अर्थ तटस्थता या अलगाववाद नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर गुण-दोष के आधार पर स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता बनाए रखना है। यह नीति विकासशील राष्ट्रों को अपनी संप्रभुता सुरक्षित रखने और विदेशी प्रभाव से बचने में सहायता करती है। इसके माध्यम से राष्ट्र वैश्विक शांति और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय भूमिका निभाते हैं और किसी सैन्य गठबंधन का हिस्सा नहीं बनते।

Downloaded from www.pdf.tube

क्षेत्रफल, जनसंख्या का आकार, उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन और सैन्य क्षमता शामिल हैं। ये तत्व राष्ट्र की शक्ति का भौतिक आधार तैयार करते हैं और उसकी आर्थिक एवं सुरक्षा क्षमता का निर्धारण करते हैं। हालांकि अमूर्त तत्व भी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन मूर्त तत्व वे ठोस संसाधन हैं जिनका उपयोग राज्य अपनी नीतियों को लागू करने और वैश्विक मंच पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए प्रभावी रूप से करते हैं।

72. (C) सुरक्षा दुविधा जिसके कारण शस्त्रों की दौड़ होती है
सुरक्षा दुविधा एक ऐसी स्थिति है जहाँ एक राज्य द्वारा अपनी सुरक्षा बढ़ाने हेतु किए गए कार्य अनजाने में दूसरे राज्य की असुरक्षा बढ़ा देते हैं। जब एक देश रक्षा बजट बढ़ाता है, तो पड़ोसी देश इसे संभावित हमले की तैयारी मानता है और स्वयं भी हथियार जुटाने लगता है। इससे दोनों देशों की सुरक्षा बढ़ने के बजाय कुल तनाव बढ़ जाता है और वे एक महंगी शस्त्रों की दौड़ में फंस जाते हैं। यह चक्र इस अविश्वास का परिणाम है कि अराजक विश्व में कोई भी सैन्य वृद्धि केवल रक्षात्मक नहीं हो सकती।

73. (B) वैश्वीकरण
1991 के बाद वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने केवल आर्थिक क्षेत्रों को ही नहीं, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक विचारधाराओं को भी विश्व भर में फैलाया। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली और मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था का वैश्विक प्रसार इसी का हिस्सा था। सूचना क्रांति और अंतर्राष्ट्रीय संचार के माध्यम से पश्चिमी मूल्यों और संस्थानों ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों को गहराई से प्रभावित किया। इसने राष्ट्रों के बीच की दूरियों को कम किया और एक ऐसी परस्पर जुड़ी दुनिया बनाई जहाँ विचार और व्यवस्थाएं सीमाओं की परवाह किए बिना तेजी से प्रवाहित होती हैं और प्रभाव डालती हैं।

74. (B) P-3, Q-2, R-1, S-4
राष्ट्रीय हित वे लक्ष्य हैं जिन्हें राष्ट्र सुरक्षा और समृद्धि हेतु अपनाता है। शक्ति दूसरों के व्यवहार को प्रभावित करने की क्षमता को दर्शाती है, जबकि विचारधारा विश्वासों का एक सुसंगत समूह है। कूटनीति वह निरंतर अभ्यास है जिसके माध्यम से राज्य आपस में संवाद करते हैं और अपने संबंधों का प्रबंधन करते हैं। ये चारों अवधारणाएं मिलकर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की पूरी रूपरेखा तैयार करती हैं, जहाँ राज्य अपने हितों की पूर्ति हेतु विचारधारा और कूटनीति का सहारा लेते हुए शक्ति का प्रयोग करते हैं और वैश्विक स्तर पर अपनी स्थिति मजबूत करते हैं।

75. (D) संप्रभुता
संप्रभुता का तात्पर्य राज्य की उस सर्वोच्च सत्ता से है जिसके अंतर्गत वह अपने क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण रखता है और बाहरी हस्तक्षेप से मुक्त होता है। यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का वह मौलिक सिद्धांत है जो एक राज्य को अन्य सभी संस्थाओं से स्वतंत्र बनाता है। संप्रभु राज्य के ऊपर कोई ऐसी वैधानिक सत्ता नहीं होती जो उसे आदेश दे सके, हालांकि वह अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन स्वेच्छा से करता है। यह अवधारणा राज्यों की स्वतंत्रता और समानता का कानूनी आधार प्रदान करती है और वैश्विक व्यवस्था को व्यवस्थित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

76. (B) एक अंतर-राज्यीय युद्ध
जब दो या अधिक संप्रभु देशों की नियमित सेनाओं के बीच पारंपरिक हथियारों का उपयोग करके संघर्ष होता है, तो उसे अंतर-राज्यीय युद्ध कहा जाता है। यह आंतरिक गृहयुद्धों से भिन्न होता है क्योंकि इसमें शामिल पक्ष स्वतंत्र राष्ट्र होते हैं। ऐसे युद्ध आमतौर पर सीमा विवाद, संसाधनों के नियंत्रण या राजनीतिक वर्चस्व के लिए लड़े जाते हैं। यद्यपि आधुनिक युग में ऐसे युद्धों की संख्या कम हुई है, फिर भी वे अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और वैश्विक स्थिरता के लिए सबसे बड़ा पारंपरिक खतरा बने हुए हैं, जिससे व्यापक जनहानि संभव है।

77. (C) कथन I सत्य है, लेकिन कथन II असत्य है।
यथार्थवादी दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को निरंतर शक्ति संघर्ष के रूप में देखता है, जहाँ राज्य अपने स्वार्थों और सुरक्षा से प्रेरित होते हैं। यह विचारधारा मानती है कि अराजक विश्व में नैतिकता का स्थान राष्ट्रीय सुरक्षा के बाद आता है। कथन II गलत है क्योंकि यथार्थवादी राष्ट्रहित को ही सर्वोच्च नैतिकता मानते हैं और उनका मानना है कि आदर्शवादी मूल्यों के पीछे पड़ना राज्य के अस्तित्व को खतरे में डाल सकता है। उनके अनुसार, शांति केवल शक्ति संतुलन और सैन्य मजबूती के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है, न कि केवल नैतिक अपीलों से।

78. (A) व्यवस्था दृष्टिकोण
व्यवस्था दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विश्लेषण एक 'सिस्टम' के रूप में करता है जहाँ विभिन्न राज्य इसकी इकाइयां हैं। यह इन इकाइयों के बीच मांगों और सहयोग के निरंतर प्रवाह पर ध्यान केंद्रित करता है। यह मानता है कि व्यवस्था की समग्र संरचना और उसके भीतर होने वाली अंतःक्रियाएं राज्यों के व्यवहार को निर्धारित करती हैं। यह व्यक्तिगत घटनाओं के बजाय व्यापक पैटर्न और संरचनात्मक स्थिरता को समझने का प्रयास करता है। यह राजनीति को एक जीवंत और परस्पर जुड़ी प्रक्रिया के रूप में विश्लेषित करता है जहाँ वैश्विक ढांचे की भूमिका प्राथमिक होती है।

79. (B) सक्रिय रूप से पूर्ण निरस्त्रीकरण और सेना को समाप्त करने का प्रयास करना
शक्ति के अधिग्रहण का अर्थ है उन संसाधनों और क्षमताओं को बढ़ाना जो दूसरे देशों को प्रभावित कर सकें। इसमें मजबूत अर्थव्यवस्था का निर्माण, सैन्य शक्ति का विकास और रणनीतिक गठबंधन बनाना शामिल है, क्योंकि ये सभी राज्य के प्रभाव को बढ़ाते हैं। इसके विपरीत, अपनी सेना को पूरी तरह समाप्त करना राज्य की शक्ति को कम करता है और उसे दूसरों के प्रति असुरक्षित बनाता है। यथार्थवादी दृष्टिकोण में शक्ति संचय अस्तित्व की रक्षा हेतु आवश्यक है, जबकि सैन्य विहीन होना कमजोरी का प्रतीक माना जाता है जो संप्रभुता को खतरे में डालता है।

NODIA

28. (B) युद्ध की प्रकृति और कारण राजनीतिक, आर्थिक या वैचारिक हो सकते हैं।
युद्ध एक अत्यंत जटिल घटना है जिसकी प्रकृति बहुआयामी होती है। इसके पीछे राजनीतिक वर्चस्व, संसाधनों का नियंत्रण, वैचारिक मतभेद या ऐतिहासिक जातीय शत्रुता जैसे अनेक कारण हो सकते हैं। युद्ध के स्वरूप भी समय के साथ बदलते रहे हैं, जो सीमित क्षेत्रीय संघर्ष से लेकर व्यापक वैश्विक युद्ध तक हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून संघर्षों को कम करने का प्रयास करता है, लेकिन इसे पूरी तरह समाप्त करने में सफल नहीं रहा है। युद्ध की जटिलता इसे समझने हेतु विभिन्न आयामों के विश्लेषण की मांग करती है।

29. (C) कुछ हथियारों के उत्पादन, तैनाती या उपयोग को विनियमित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय या द्विपक्षीय समझौते।
शस्त्र नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य हथियारों की प्रतिस्पर्धा को विनियमित करना है ताकि युद्ध की संभावना और उसकी विनाशकता को कम किया जा सके। यह पूर्ण निरस्त्रीकरण से भिन्न है क्योंकि इसमें हथियारों को समाप्त करने के बजाय उनके प्रसार पर सीमाएं लगाई जाती हैं। इसके माध्यम से राज्यों के बीच विश्वास बढ़ाया जाता है और आकस्मिक युद्ध के खतरों को टाला जाता है। ये समझौते अक्सर विशिष्ट श्रेणियों के हथियारों, जैसे परमाणु मिसाइल या रासायनिक हथियारों की तैनाती को नियंत्रित करने के लिए किए जाते हैं।

30. (A) 1, 3, 2, 4
विवाद निपटान की प्रक्रिया आमतौर पर सबसे शांतिपूर्ण चरणों से शुरू होती है। सर्वप्रथम राजनयिक वार्ता के माध्यम से संचार स्थापित किया जाता है। यदि यह विफल रहता है, तो तीसरे पक्ष की मध्यस्थता का सहारा लिया जाता है। अगले चरण में दबाव बनाने के लिए राजनयिक संबंधों को विच्छेद किया जा सकता है। अंततः, जब सभी शांतिपूर्ण मार्ग बंद हो जाते हैं, तब सीमित सैन्य हस्तक्षेप जैसे कठोर कदम उठाए जाते हैं। यह क्रम दर्शाता है कि कैसे राष्ट्र शांतिपूर्ण तरीकों को प्राथमिकता देते हुए धीरे-धीरे बल प्रयोग की ओर बढ़ते हैं।

31. (A) शून्य-योग खेल
शून्य-योग खेल एक ऐसी रणनीतिक स्थिति है जहाँ एक पक्ष का लाभ अनिवार्य रूप से दूसरे पक्ष की समान मात्रा में हानि के बराबर होता है। इसमें कुल लाभ और हानि का योग सदैव शून्य रहता है, जिसका अर्थ है कि यहाँ सहयोग की कोई गुंजाइश नहीं होती। यथार्थवादी विचारक अक्सर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को इसी दृष्टिकोण से देखते हैं, जहाँ एक राज्य की सुरक्षा में वृद्धि को दूसरे की कमजोरी माना जाता है। यह परस्पर विरोधी हितों वाली अत्यंत कठोर प्रतिस्पर्धी स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है, जहाँ केवल एक की जीत संभव है।

32. (B) यह निर्धारित करती है कि नीति निर्माता घटनाओं की व्याख्या कैसे करते हैं और प्रतिक्रियाएँ कैसे तैयार करते हैं।
राष्ट्रीय हित केवल वस्तुनिष्ठ तथ्यों पर आधारित नहीं होता, बल्कि इस पर नीति निर्माताओं की धारणाओं का गहरा प्रभाव पड़ता है। किसी खतरे या अवसर को नेता किस प्रकार देखते हैं, यही उनकी प्रतिक्रिया और विदेश नीति की दिशा तय करता है। धारणा ही वह चश्मा है जिसके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का विश्लेषण किया जाता है। यदि नेतृत्व किसी स्थिति को अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता है, तो वह आक्रामक नीतियां अपना सकता है। इसलिए, व्यक्तिपरक समझ राष्ट्रीय हित के व्यावहारिक अनुप्रयोग में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

33. (C) कथन I सत्य है, लेकिन कथन II असत्य है।
शीतयुद्ध के समापन के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका एकमात्र महाशक्ति के रूप में उभरा, जिससे एकध्रुवीय व्यवस्था का उदय हुआ। हालांकि, वैश्वीकरण ने राष्ट्र-राज्यों की संप्रभुता को सुदृढ़ करने के बजाय उसे कई मायनों में सीमित किया है। आर्थिक परस्पर निर्भरता और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की भूमिका ने राज्यों के घरेलू मामलों पर उनके पारंपरिक नियंत्रण को कमजोर किया है। अतः वैश्वीकरण संप्रभुता के लिए एक चुनौती बनकर उभरा है, न कि उसे पूर्णतः सशक्त करने वाला कारक। राज्यों की निर्णय लेने की शक्ति अब वैश्विक प्रवाह से प्रभावित होती है।

34. (D) एकपक्षीय सैन्य विजय
कूटनीति का प्राथमिक उद्देश्य राज्यों के बीच शांतिपूर्ण संबंधों का संचालन करना है। इसमें वार्ता करना, अपने देश का प्रतिनिधित्व करना और विदेशों की स्थितियों की रिपोर्ट भेजना शामिल है। एकपक्षीय सैन्य विजय कूटनीति का कार्य नहीं है, बल्कि यह कूटनीति की विफलता और बल प्रयोग का प्रतीक है। कूटनीति का कौशल इस बात में निहित है कि वह बिना युद्ध के राष्ट्रीय हितों को कैसे प्राप्त करती है। जब कोई देश सेना का सहारा लेकर विजय प्राप्त करता है, तो वह कूटनीतिक दायरे से बाहर निकलकर प्रत्यक्ष संघर्ष में प्रवेश करता है।

35. (C) व्यवस्था दृष्टिकोण
व्यवस्था दृष्टिकोण यह मानता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को केवल राज्यों के आंतरिक कार्यों से नहीं समझा जा सकता, बल्कि इसके लिए संपूर्ण व्यवस्था की संरचना को देखना आवश्यक है। यह दृष्टिकोण इस बात पर जोर देता है कि शक्ति का वैश्विक वितरण (जैसे एकध्रुवीय या द्विध्रुवीय व्यवस्था) यह तय करता है कि राज्य एक-दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। यहाँ व्यवस्था ही वह ढांचा है जो राज्यों की स्वायत्तता को सीमित करती है और उनके विकल्पों को प्रभावित करती है। इस विश्लेषण में राज्यों को व्यवस्था के भीतर सक्रिय इकाइयों के रूप में देखा जाता है।

36. (B) पाक्टा संट सरवेंडा
अंतर्राष्ट्रीय कानून का 'पाक्टा संट सरवेंडा' सिद्धांत यह स्थापित करता है कि राज्यों द्वारा स्वेच्छा से हस्ताक्षरित संधियाँ उनके लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी हैं और उनका पालन सद्भावना के साथ किया जाना चाहिए। यह सिद्धांत संधि कानून की आधारशिला है, जो वैश्विक व्यवस्था में विश्वसनीयता सुनिश्चित करता है। इसके बिना अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। यह राज्यों को उनके द्वारा किए गए वादों के प्रति उत्तरदायी बनाता है और अराजक अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में विधिक अनुशासन और सहयोग का वातावरण निर्मित करता है।

Click Here to Buy book on Amazon

प्रक्रिया अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कानून के शासन और न्याय को सुदृढ़ करती है।

89. (A) निर्णय-प्रक्रिया दृष्टिकोण
निर्णय-प्रक्रिया दृष्टिकोण का केंद्र यह विश्लेषण करना है कि किसी देश की विदेश नीति का निर्माण वास्तव में कैसे होता है। यह केवल बाहरी परिस्थितियों को नहीं देखता, बल्कि राज्य के भीतर मौजूद विभिन्न विभागों के बीच के तनाव और नेताओं के व्यक्तिगत विश्वासों की गहराई से जांच करता है। यह दृष्टिकोण मानता है कि नीति निर्माण एक जटिल प्रक्रिया है जहाँ आंतरिक संघर्ष और व्यक्तिगत सोच का परिणाम अंतिम निर्णय के रूप में निकलता है। यह राज्य की एकात्मक छवि के भीतर छिपी हुई विविधता को उजागर करता है और वास्तविक निर्णय प्रक्रिया को स्पष्ट करता है।

90. (A) 1, 3, 2, 4
विवाद निपटान की प्रक्रिया आमतौर पर सबसे शांतिपूर्ण चरणों से शुरू होती है। सर्वप्रथम राजनयिक वार्ता और विरोध के माध्यम से संचार स्थापित किया जाता है। यदि यह विफल रहता है, तो तीसरे पक्ष की मध्यस्थता या कानूनी अधिनिर्णय का सहारा लिया जाता है। अगले चरण में दबाव बनाने के लिए राजनयिक संबंधों को विच्छेद किया जा सकता है। अंततः, जब सभी शांतिपूर्ण मार्ग बंद हो जाते हैं, तब सैन्य हस्तक्षेप जैसे कठोर कदम उठाए जाते हैं। यह क्रम दर्शाता है कि कैसे राष्ट्र शांतिपूर्ण तरीकों को प्राथमिकता देते हुए धीरे-धीरे बल प्रयोग की ओर बढ़ते हैं।

91. (C) यथार्थवाद
यथार्थवादी दृष्टिकोण यह मानता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई स्थायी मित्र या शत्रु नहीं होता, केवल स्थायी राष्ट्रीय हित होते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार, राज्य गठबंधन केवल तभी बनाते हैं जब उन्हें किसी सामान्य शक्तिशाली शत्रु से खतरा महसूस होता है। जैसे ही वह खतरा समाप्त होता है या हित बदल जाते हैं, ये गठबंधन टूट जाते हैं या अप्रासंगिक हो जाते हैं। यथार्थवादियों के लिए गठबंधन सुरक्षा प्राप्त करने का एक व्यावहारिक साधन है, न कि कोई नैतिक प्रतिबद्धता। यह राज्यों के बीच शक्ति संतुलन बनाए रखने की एक निरंतर चलने वाली रणनीतिक प्रक्रिया है।

92. (A) खेल सिद्धांत
खेल सिद्धांत इस आधारभूत धारणा पर कार्य करता है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर राज्य तर्कसंगत अभिनेता हैं जो अपने लाभ को अधिकतम करने और नुकसान को कम करने के लिए निर्णय लेते हैं। यह सिद्धांत यह विश्लेषण करता है कि कैसे एक राज्य का चुनाव दूसरे राज्य के संभावित निर्णयों से प्रभावित होता है। इसमें राज्यों को ऐसे खिलाड़ियों के रूप में देखा जाता है जो रणनीतिक खेल में अपने हितों की रक्षा के लिए सर्वोत्तम चालें चलते हैं। यह संघर्ष और सहयोग की स्थितियों में तर्कसंगत विकल्पों को समझने के लिए एक वैज्ञानिक ढांचा प्रदान करता है।

93. (D) कथन I असत्य है, लेकिन कथन II सत्य है।
वैश्वीकरण केवल एक आर्थिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह राजनीति, संस्कृति और समाज के हर पहलू को प्रभावित करने वाली एक बहुआयामी घटना है। कथन II सही है क्योंकि वैश्वीकरण ने राष्ट्र-राज्यों के एकाधिकार को कम किया है और बहुराष्ट्रीय निगमों तथा अंतर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठनों जैसे प्रभावशाली गैर-राज्य अभिनेताओं को वैश्विक मंच पर एक नई पहचान दी है। ये अभिनेता अब नीतियों के निर्माण और अंतर्राष्ट्रीय जनमत को आकार देने में राज्यों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। अतः वैश्वीकरण ने विश्व राजनीति के पारंपरिक ढांचों को व्यापक रूप से बदल दिया है।

94. (D) एक जातीय संघर्ष या गृहयुद्ध
जब किसी एक ही देश की सीमाओं के भीतर अलग-अलग पहचान समूहों या समुदायों के बीच हथियारों के साथ संघर्ष होता है, तो उसे जातीय संघर्ष या गृहयुद्ध कहा जाता है। ऐसे संघर्ष अक्सर सत्ता के बंटवारे, संसाधनों के नियंत्रण या अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान की सुरक्षा के लिए होते हैं। ये युद्ध अंतर-राज्यीय युद्धों से अधिक विनाशकारी हो सकते हैं क्योंकि इनमें समाज पूरी तरह विभाजित हो जाता है और मानवीय संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। शीतयुद्ध के बाद के युग में ऐसे आंतरिक संघर्षों की संख्या में वैश्विक स्तर पर काफी वृद्धि हुई है।

95. (B) निरस्त्रीकरण
निरस्त्रीकरण वह प्रक्रिया या लक्ष्य है जिसका उद्देश्य हथियारों की संख्या में प्रभावी कटौती करना या हथियारों की एक विशिष्ट श्रेणी को पूरी तरह समाप्त करना है। यह शस्त्र नियंत्रण से अधिक महत्वाकांक्षी है क्योंकि यह केवल प्रबंधन नहीं बल्कि उन्मूलन पर बल देता है। इसका मुख्य तर्क यह है कि हथियारों की अनुपस्थिति ही युद्ध की संभावना को जड़ से समाप्त कर सकती है और वैश्विक शांति सुनिश्चित कर सकती है। निरस्त्रीकरण के माध्यम से राष्ट्र अपने सैन्य खर्च को कम करके उन संसाधनों का उपयोग जनकल्याण और आर्थिक विकास के लिए कर सकते हैं।

96. (C) संप्रभुता
संप्रभुता का अर्थ राज्य की वह अनन्य शक्ति है जो उसे अपने क्षेत्र के भीतर सर्वोच्च निर्णय लेने का अधिकार प्रदान करती है और बाहरी शक्तियों को हस्तक्षेप करने से रोकती है। इसके अंतर्गत राज्य अपनी जनसंख्या को नियंत्रित करने, कानून बनाने और अपने संसाधनों का उपयोग करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होता है। यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की आधारशिला है क्योंकि यह प्रत्येक राज्य को एक स्वतंत्र और समान इकाई के रूप में पहचान दिलाती है। संप्रभुता के बिना कोई भी देश अपनी आंतरिक शांति और बाहरी सुरक्षा को स्वायत्त रूप से सुनिश्चित नहीं कर सकता है।

97. (D) मृदु शक्ति के माध्यम से राष्ट्रीय हित का प्रचार।
मृदु शक्ति का तात्पर्य सैन्य या आर्थिक दबाव के बजाय सांस्कृतिक आकर्षण, राजनीतिक मूल्यों और न्यायपूर्ण विदेश नीतियों के माध्यम से दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता से है।

Downloaded from www.pdf.tube

टूटने का संकेत थी जिसने दशकों तक विश्व को दो वैचारिक गुटों में बांट रखा था। इसके कुछ ही समय बाद सोवियत संघ का आधिकारिक विघटन हुआ, जिससे द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था का पूर्णतः समापन हो गया और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के एक नए युग का सूत्रपात हुआ।

149. (C) यह प्रवर्तन के लिए एक केंद्रीकृत विश्व पुलिस बल पर भारी निर्भर करता है।
अंतर्राष्ट्रीय कानून की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें घरेलू कानून की तरह कोई केंद्रीकृत विश्व पुलिस बल या दंड देने वाली सर्वोच्च सत्ता नहीं है। कानूनों का पालन मुख्य रूप से राज्यों की सहमति, पारस्परिक लाभ के बोध और अंतर्राष्ट्रीय जनमत के दबाव पर निर्भर करता है। यद्यपि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कुछ स्थितियों में बल प्रयोग की अनुमति दे सकती है, लेकिन यह किसी स्थायी वैश्विक पुलिस व्यवस्था के समान नहीं है। प्रवर्तन अक्सर स्वयं राज्यों द्वारा जवाबी उपायों या कूटनीतिक दबाव के माध्यम से किया जाता है। अतः कथन C अंतर्राष्ट्रीय कानून की वास्तविक संरचना के बारे में गलत है।

150. (A) 2, 4, 3, 1
एक अंतर्राष्ट्रीय संधि के निर्माण की प्रक्रिया अत्यंत व्यवस्थित होती है। सर्वप्रथम, संबंधित राज्य किसी विषय पर चर्चा के लिए वार्ता करते हैं और संधि का मसौदा तैयार करते हैं। प्रारूप तैयार होने के बाद, राज्यों के प्रतिनिधि उस पर हस्ताक्षर करते हैं, जो सहमति का प्राथमिक संकेत है। इसके बाद, प्रत्येक देश को अपने आंतरिक विधिक नियमों के अनुसार संधि का अनुसमर्थन करना होता है। अंततः, जब आवश्यक संख्या में देश अनुसमर्थन कर देते हैं, तब संधि आधिकारिक रूप से प्रभावी और लागू हो जाती है। यह क्रम कानूनी प्रतिबद्धता की क्रमिक वृद्धि को दर्शाता है।

151. (B) प्रतिस्पर्धी और प्रचारक विचारधारा वाले दो राज्य एक-दूसरे को खतरे के रूप में देखते हैं।
विचारधारा संघर्ष का स्रोत तब बनती है जब वह अनन्य और विस्तारवादी हो जाती है। यदि दो राज्य विरोधी मूल्यों को अपनाते हैं और प्रत्येक अपनी व्यवस्था को श्रेष्ठ मानकर उसे दूसरे पर थोपने या उसका प्रचार करने का प्रयास करता है, तो उनमें गहरा अविश्वास और असुरक्षा पैदा होती है। शीतयुद्ध इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहाँ वैचारिक मतभेदों ने पूरी दुनिया को तनाव और शस्त्रों की दौड़ के किनारे खड़ा कर दिया था। यहाँ विचारधारा केवल व्यक्तिगत विश्वास नहीं रहती, बल्कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा और वैश्विक प्रभुत्व के संघर्ष का एक शक्तिशाली हथियार बन जाती है।

152. (A) न्यायिक समाधान या अधिनिर्णय
विवाद निपटान की अन्य पद्धतियों जैसे वार्ता, मध्यस्थता या सद्भावना सेवा में समाधान पूरी तरह से पक्षों की सहमति पर निर्भर करता है और कोई बाहरी पक्ष उन पर अपनी इच्छा नहीं थोप सकता। इसके विपरीत, न्यायिक समाधान या अधिनिर्णय में मामला अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जैसे विधिक निकाय को सौंपा जाता है। अदालत का फैसला दोनों पक्षों के लिए अंतिम और कानूनी रूप से बाध्यकारी होता है। इसका पालन करना अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत एक अनिवार्य दायित्व है। यह प्रक्रिया विवादों को कानून के दायरे में और पूरी निष्पक्षता के साथ समाप्त करने का सबसे औपचारिक मार्ग है।

153. (D) मृदु शक्ति
मृदु शक्ति का तात्पर्य सैन्य बल या आर्थिक दबाव के स्थान पर आकर्षण और अनुनय के माध्यम से दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता है। इसमें किसी देश की संस्कृति, कला, शिक्षा व्यवस्था, लोकतांत्रिक आदर्श और नैतिक विदेश नीति की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। जब अन्य राष्ट्रों के लोग और सरकारें किसी देश के मूल्यों से प्रभावित होकर स्वतः ही उसका सहयोग करने लगते हैं, तो वह राष्ट्र मृदु शक्ति का सफल प्रयोग कर रहा होता है। यह अवधारणा आधुनिक कूटनीति में अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दीर्घकालिक प्रभाव और सम्मान बनाने में सहायक होती है।

154. (C) व्यवस्था सिद्धांत
व्यवस्था सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को एक समग्र ढांचे के रूप में देखता है जहाँ व्यक्तिगत राज्यों के व्यवहार को अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना द्वारा समझा जा सकता है। यह मानता है कि शक्ति का वितरण यह निर्धारित करता है कि राज्यों के पास कितने विकल्प हैं और वे एक-दूसरे के प्रति कैसा व्यवहार करेंगे। इस दृष्टिकोण के अनुसार, राज्य एक व्यापक प्रणाली के अंग हैं और उनकी स्वायत्तता उस व्यवस्था के नियमों और बाधाओं से सीमित होती है। यह विश्लेषण राज्य के आंतरिक स्वरूप के बजाय वैश्विक ढांचे के प्रभाव को प्राथमिकता देता है।

155. (D) कथन I असत्य है, लेकिन कथन II सत्य है।
गठबंधन कभी भी स्थायी नहीं होते, वे बदलती सुरक्षा परिस्थितियों और राष्ट्रीय हितों के आधार पर बनाए और तोड़े जाते हैं। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा है जहाँ पुराने शत्रु मित्र बन गए और पुराने गठबंधन टूट गए। कथन II सही है क्योंकि गठबंधन शक्ति संतुलन बनाए रखने का एक प्रमुख कूटनीतिक साधन है। राज्य किसी शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी से अपनी रक्षा करने के लिए अन्य समान विचारधारा वाले या समान खतरे का सामना करने वाले राष्ट्रों के साथ जुड़ते हैं। यह यथार्थवादी राजनीति का एक अनिवार्य हिस्सा है जो सामूहिक सुरक्षा और शक्ति के वितरण को प्रभावित करता है।

156. (B) निवारण
निवारण का मुख्य उद्देश्य संभावित आक्रमणकारी को यह विश्वास दिलाना है कि युद्ध शुरू करने की स्थिति में उसे असहनीय क्षति उठानी पड़ेगी। यह नीति 'भय' के रणनीतिक उपयोग पर आधारित है। परमाणु युग में, निवारण ने महाशक्तियों के बीच प्रत्यक्ष युद्ध को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई क्योंकि दोनों पक्ष जानते थे कि हमले का परिणाम दोनों का विनाश होगा। निवारण केवल सैन्य तैयारी नहीं है, बल्कि यह शत्रु के मानस को प्रभावित करने का एक कूटनीतिक उपकरण है। यह शांति को सहयोग के बजाय 'बदले के डर' के माध्यम से सुरक्षित करने का एक तरीका है।

NODIA

106. (A) सीमा विवाद को हल करने के लिए बिना उकसावे के सैन्य हमला करना।
अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत राज्यों का यह अनिवार्य दायित्व है कि वे अपने विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाएं। वार्ता, मध्यस्थता और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का सहारा लेना कानूनसम्मत और शांतिपूर्ण मार्ग हैं। इसके विपरीत, बिना किसी ठोस कानूनी आधार या उकसावे के सैन्य हमला करना संप्रभुता और 'विवादों के शांतिपूर्ण समाधान' के सिद्धांत का गंभीर उल्लंघन है। बल प्रयोग करना न केवल अवैध है, बल्कि यह क्षेत्रीय और वैश्विक शांति के लिए खतरा पैदा करता है। राज्य से सदैव यह अपेक्षा की जाती है कि वह हिंसा से पूर्व सभी कूटनीतिक विकल्पों का उपयोग करे।

107. (C) भौगोलिक सीमाएँ और राज्य संप्रभुता
वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने दुनिया को एक एकीकृत व्यवस्था में बदल दिया है, जहाँ सूचना, पूंजी और लोगों का प्रवाह राष्ट्रीय सीमाओं की परवाह बिना होता है। इसके कारण भौगोलिक सीमाओं का महत्व कम हो गया है और राष्ट्र-राज्यों की पारंपरिक संप्रभुता की अवधारणा को चुनौती मिली है। अब राज्य अपने घरेलू मामलों में पूरी तरह स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पाते, क्योंकि उन्हें वैश्विक बाजारों और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करना पड़ता है। यह परस्पर संबद्धता दर्शाती है कि आधुनिक युग में कोई भी राष्ट्र एकांत में रहकर प्रगति नहीं कर सकता, जिससे राज्य का नियंत्रण शिथिल हुआ है।

108. (A) खेल सिद्धांत दृष्टिकोण
खेल सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के उन रणनीतिक पहलुओं का अध्ययन करता है जहाँ प्रत्येक अभिनेता के विकल्प और उनके परिणाम एक-दूसरे पर निर्भर होते हैं। 'पे-ऑफ मैट्रिक्स' का उपयोग यह दर्शाने के लिए किया जाता है कि विभिन्न परिस्थितियों में राज्यों को कितना लाभ या हानि होगी। यह दृष्टिकोण मानता है कि राज्य तर्कसंगत गणनाओं के आधार पर वह विकल्प चुनते हैं जो उनके हितों को अधिकतम करे। यह विशेष रूप से संकट के समय और शस्त्रों की दौड़ जैसी स्थितियों में राज्यों के व्यवहार को समझने के लिए उपयोगी है।

109. (D) इसका निर्धारण एक राजनीतिक प्रक्रिया है जो देश के नेतृत्व से प्रभावित होती है।
राष्ट्रीय हित कोई ऐसी जड़ अवधारणा नहीं है जो सभी राज्यों के लिए समान हो या जो कभी बदले नहीं। यह वास्तव में देश के राजनीतिक नेतृत्व, उसकी विचारधारा और जनता की आकांक्षाओं द्वारा परिभाषित किया जाता है। समय के साथ बदलती वैश्विक परिस्थितियों और आंतरिक जरूरतों के अनुसार राष्ट्रीय हित के लक्ष्यों में भी परिवर्तन होता रहता है। यह नीति निर्माताओं की उस निरंतर चलने वाली बहस और विश्लेषण का परिणाम है जिसमें वे तय करते हैं कि राष्ट्र की सुरक्षा और समृद्धि के लिए वर्तमान में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है।

110. (D) 1, 2 और 3
राज्य अपने राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने और वैश्विक मंच पर अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए उपकरणों की एक विस्तृत श्रृंखला का उपयोग करते हैं। कूटनीति और वार्ता प्रारंभिक और शांतिपूर्ण साधन हैं। यदि इनसे काम नहीं बनता, तो वे आर्थिक सहायता देकर मित्रता बढ़ा सकते हैं या प्रतिबंध लगाकर दबाव डाल सकते हैं। अंततः, गंभीर स्थितियों में सैन्य बल का उपयोग या गठबंधन बनाना शक्ति प्रदर्शन के प्रभावी तरीके हैं। ये सभी उपकरण मिलकर किसी देश की विदेश नीति की क्षमता को परिभाषित करते हैं, जिनका उपयोग परिस्थितियों के अनुसार संतुलित ढंग से किया जाता है।

111. (A) दार्शनिक बहस के युद्ध
अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में युद्धों को उनके उद्देश्यों और प्रयुक्त साधनों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। जातीय विवाद, परमाणु युद्ध और जैव-रासायनिक युद्ध संघर्ष के वास्तविक और विनाशकारी स्वरूप हैं जिनमें हथियारों और सेनाओं का प्रयोग होता है। इसके विपरीत, 'दार्शनिक बहस' विचारों का आदान-प्रदान है जिसे 'युद्ध' की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता क्योंकि इसमें हिंसा या सैन्य बल शामिल नहीं होता। युद्ध का अर्थ अनिवार्य रूप से दो या दो से अधिक पक्षों के बीच सशस्त्र संघर्ष है, जबकि दार्शनिक मतभेद कूटनीतिक या शैक्षणिक चर्चाओं का हिस्सा होते हैं।

112. (C) शक्ति संतुलन
शक्ति संतुलन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक पारंपरिक सिद्धांत है जो यह मानता है कि शांति तभी बनी रह सकती है जब कोई एक राज्य इतना शक्तिशाली न हो जाए कि वह अन्य सभी पर हावी हो सके। यदि कोई देश अपनी शक्ति बहुत अधिक बढ़ाता है, तो अन्य राज्य उसके विरुद्ध गठबंधन बनाकर या अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाकर उसे संतुलित करने का प्रयास करते हैं। इसका उद्देश्य किसी भी राष्ट्र को वर्चस्व स्थापित करने से रोकना और व्यवस्था में स्थिरता बनाए रखना है। यह यथार्थवादी विचारधारा का एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो राज्यों के बीच निरंतर प्रतिस्पर्धा को प्रबंधित करता है।

113. (B) कथन I और कथन II दोनों असत्य हैं।
शस्त्र नियंत्रण का अर्थ सभी हथियारों का विनाश नहीं, बल्कि उनके प्रसार और उपयोग को विनियमित और प्रबंधित करना है ताकि युद्ध के जोखिम को कम किया जा सके। दूसरी ओर, निरस्त्रीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें हथियारों की संख्या में वास्तविक कटौती की जाती है या उन्हें पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य रखा जाता है। कथन I गलत है क्योंकि शस्त्र नियंत्रण केवल नियमन की बात करता है, और कथन II गलत है क्योंकि उसने निरस्त्रीकरण की परिभाषा को शस्त्र नियंत्रण के साथ मिला दिया है। ये दोनों अवधारणाएं हथियारों की प्रतिस्पर्धा को कम करने के अलग-अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करती हैं।

114. (A) अंतर्राष्ट्रीय कानून।
अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक अत्यंत महत्वपूर्ण भाग युद्ध के समय राज्यों के व्यवहार को नियंत्रित करने वाले नियमों से संबंधित है, जिसे 'युद्ध का कानून' भी कहा जाता है। ये नियम नागरिकों की सुरक्षा, युद्धबंदियों के साथ मानवीय व्यवहार और प्रतिबंधित हथियारों के उपयोग को सुनिश्चित करते हैं। इसका उद्देश्य सशस्त्र संघर्ष की विभीषिका को सीमित करना और हिंसा के बीच भी मानवीय गरिमा को बनाए रखना है।

Click Here to Buy book on Amazon

संधियाँ जैसे जिनेवा कन्वेंशन इसी विधिक ढांचे का हिस्सा हैं। यह दर्शाता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अराजकता के बावजूद कुछ स्थापित कानूनी मर्यादाएं अनिवार्य हैं।

115. (D) वैश्वीकरण का बढ़ता प्रभाव।
शीतयुद्ध के समापन के बाद की वैश्विक व्यवस्था की सबसे विशिष्ट पहचान वैश्वीकरण की प्रक्रिया रही है। सोवियत संघ के पतन के साथ ही मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था और सूचना क्रांति ने पूरी दुनिया को एक सूत्र में पिरोना शुरू कर दिया। अब राष्ट्रों के बीच संबंध केवल सैन्य शक्ति पर नहीं, बल्कि आर्थिक परस्पर निर्भरता, निवेश और सांस्कृतिक आदान-प्रदान पर अधिक आधारित हैं। हालांकि जातीय संघर्ष और नए सुरक्षा खतरे भी उभरे हैं, लेकिन देशों के बीच की दूरियों का घटना और वैश्विक स्तर पर समाजों का जुड़ना इस युग की सबसे प्रमुख प्रवृत्ति मानी जाती है।

116. (B) केवल तभी प्रभावी होता है जब वह शक्तिशाली राज्यों के हितों को दर्शाता है।
यथार्थवादी विचारक अंतर्राष्ट्रीय कानून की स्वायत्तता को लेकर संशयवादी होते हैं। वे तर्क देते हैं कि कानून में स्वयं की कोई शक्ति नहीं होती और वह केवल तभी लागू हो पाता है जब शक्तिशाली राष्ट्र उसे अपना समर्थन देते हैं। यथार्थवाद के अनुसार, यदि कोई कानून राज्य की सुरक्षा या राष्ट्रीय हित के आड़े आता है, तो राज्य उसे अनदेखा करने में संकोच नहीं करते। उनके लिए कानून वैश्विक राजनीति का नियामक नहीं, बल्कि शक्ति के वितरण का प्रतिबिंब मात्र है। वे मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अंतिम निर्णय कानून से नहीं, बल्कि शक्ति के समीकरणों से होता है।

117. (C) संधि कानून
राज्यों के बीच औपचारिक समझौतों को कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाने की पूरी प्रक्रिया संधि कानून के अंतर्गत आती है। यह विधिक ढांचा यह तय करता है कि संधियों का निर्माण कैसे होगा, उनका पालन कैसे किया जाएगा और उनके उल्लंघन पर क्या परिणाम होंगे। इसके माध्यम से ही राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने वादों को कानूनी मान्यता प्रदान करते हैं, जिससे अन्य राज्यों में विश्वास बढ़ता है। यह अराजक अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में व्यवस्था और स्थिरता लाने का एक अनिवार्य साधन है। संधियाँ ही आधुनिक कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का वास्तविक आधार निर्मित करती हैं।

118. (D) यहाँ तक कि सर्वाधिक शक्तिशाली राज्यों को भी अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की क्षमता पर बाधाओं का सामना करना पड़ता है।
अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति कभी भी निरपेक्ष या असीमित नहीं होती है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र भी हर बार अपनी इच्छा दूसरों पर नहीं थोप सकता। शक्ति की सीमाओं में अंतर्राष्ट्रीय कानून, विश्व जनमत, अन्य राज्यों द्वारा बनाया गया शक्ति संतुलन और अपने ही देश के भीतर संसाधनों एवं जनता के समर्थन की कमी शामिल है। इसके अतिरिक्त, कभी-कभी सैन्य शक्ति का उपयोग बहुत अधिक महंगा या प्रतिष्ठा के लिए हानिकारक हो सकता है। अतः शक्ति का प्रभावी प्रयोग सदैव बाहरी बाधाओं और आंतरिक सीमाओं के जटिल वातावरण के भीतर ही संभव होता है।

119. (A) संचार दृष्टिकोण
संचार दृष्टिकोण यह मानता है कि युद्ध अनिवार्य नहीं है, बल्कि यह अक्सर सूचना की कमी, गलत व्याख्या और संदेशों के त्रुटिपूर्ण विश्लेषण का परिणाम होता है। इस सिद्धांत के अनुसार, यदि राज्यों के बीच पारदर्शी और निरंतर संचार बना रहे, तो बड़ी से बड़ी गलतफहमी को दूर किया जा सकता है। युद्ध को एक 'विफलता' के रूप में देखा जाता है जो कूटनीतिक चैनलों के बंद होने या संकेतों को सही ढंग से न समझ पाने के कारण होती है। अतः सूचना के प्रवाह में सुधार करना ही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शांति बनाए रखने का सबसे प्रभावी तरीका है।

120. (B) शांतिपूर्ण समाधान : सशस्त्र संघर्ष वाला संघर्ष
शांतिपूर्ण समाधान और सशस्त्र संघर्ष एक-दूसरे के विपरीत अवधारणाएं हैं। शांतिपूर्ण समाधान का अर्थ है विवादों को बिना हिंसा के वार्ता, मध्यस्थता या कानूनी तरीकों से हल करना। इसके विपरीत, सशस्त्र संघर्ष में बल प्रयोग और युद्ध शामिल होता है। इसलिए, 'शांतिपूर्ण समाधान' को सशस्त्र संघर्ष के रूप में परिभाषित करना एक गलत युग्म है। अन्य युग्म जैसे जातीय विवाद, परमाणु युद्ध और जैव-रासायनिक युद्ध अपनी प्रकृति के अनुसार सही रूप में वर्णित हैं। संघर्ष के प्रकार और उनके निपटान के तरीके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के दो अलग-अलग आयाम हैं।

121. (C) एकध्रुवीय या बहुध्रुवीय
शीतयुद्ध के अंत के बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना को लेकर विद्वानों में मतभेद है। प्रारंभिक दौर में संयुक्त राज्य अमेरिका के एकमात्र महाशक्ति के रूप में उभरने पर इसे 'एकध्रुवीय क्षण' कहा गया। हालांकि, चीन के उदय, रूस की पुनः सक्रियता और भारत जैसे देशों की बढ़ती शक्ति के कारण कई विचारक इसे 'बहुध्रुवीय' व्यवस्था की ओर बढ़ते हुए देखते हैं। यह बहस दर्शाती है कि वैश्विक शक्ति का वितरण स्थिर नहीं है और नए केंद्रों के उदय के साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की संरचना निरंतर बदल रही है। यह शीतयुद्ध की द्विध्रुवीय स्थिरता से अधिक जटिल स्थिति है।

122. (A) अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विचारधारा की भूमिका।
जब कोई राज्य अपने संविधान में किसी विशिष्ट विचारधारा के प्रति निष्ठा व्यक्त करता है, तो वह न केवल उसके घरेलू जीवन को बल्कि उसकी विदेश नीति को भी एक निश्चित दिशा प्रदान करती है। वह राष्ट्र विश्व में अपने मित्रों और विरोधियों का चुनाव अक्सर इसी वैचारिक आधार पर करता है। उदाहरण के लिए, समाजवादी या लोकतांत्रिक देश अपनी जैसी व्यवस्था वाले राष्ट्रों के साथ सहयोग करना अधिक पसंद करते हैं। विचारधारा यहाँ राष्ट्रों के व्यवहार को प्रेरित करने और उनके वैश्विक उद्देश्यों को नैतिक रूप से परिभाषित करने वाले एक प्रमुख कारक के रूप में कार्य करती है।

NODIA

123. (D) स्वयं-सहायता
यथार्थवादी दृष्टिकोण के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में 'स्वयं-सहायता' का सिद्धांत सर्वोपरि है। चूंकि यहाँ राज्यों के ऊपर रक्षा करने वाली कोई सर्वोच्च विश्व सत्ता नहीं है, इसलिए प्रत्येक राज्य को अपने अस्तित्व और सुरक्षा के लिए स्वयं के संसाधनों और शक्ति पर निर्भर रहना पड़ता है। अराजकता की इस स्थिति में दूसरे राज्यों पर भरोसा करना जोखिम भरा माना जाता है। इसलिए, राज्य अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाते हैं और आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करते हैं। यह सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की उस कठोर वास्तविकता को दर्शाता है जहाँ प्रत्येक अभिनेता अपनी सुरक्षा का स्वयं उत्तरदायी है।

124. (B) मानवीय तर्क और सहयोग एक अधिक शांतिपूर्ण विश्व की ओर ले जा सकते हैं।
आदर्शवादी दृष्टिकोण का यह दृढ़ विश्वास है कि मनुष्य एक तर्कसंगत प्राणी है जो विनाशकारी युद्धों के बजाय शांतिपूर्ण सहयोग के लाभों को समझ सकता है। यह विचारधारा मानती है कि यदि सही अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, नियम और शिक्षा प्रदान की जाए, तो राष्ट्र अपने स्वार्थों को त्यागकर सामूहिक कल्याण के लिए कार्य कर सकते हैं। आदर्शवादियों के अनुसार, युद्ध कोई प्राकृतिक घटना नहीं है बल्कि इसे मानवीय प्रयासों और कूटनीति के माध्यम से पूरी तरह समाप्त किया जा सकता है। यह दृष्टिकोण वैश्विक सद्भाव और न्यायपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की स्थापना की संभावना पर आधारित है।

125. (C) ऐसी स्थिति जहाँ अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक राज्य द्वारा की गई कार्रवाइयों को अन्य राज्यों द्वारा खतरे के रूप में देखा जाता है, जिससे वे भी वैसी ही प्रतिक्रिया करते हैं।
सुरक्षा दुविधा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की एक विडंबनापूर्ण स्थिति है जहाँ एक राज्य का रक्षात्मक कदम दूसरे के लिए आक्रामक संकेत बन जाता है। जब कोई राष्ट्र अपनी सुरक्षा के लिए हथियार बढ़ाता है, तो उसका पड़ोसी असुरक्षित महसूस करता है और वह भी सैन्य वृद्धि शुरू कर देता है। इसके परिणामस्वरूप दोनों ही राष्ट्र पहले की तुलना में कम सुरक्षित हो जाते हैं और हथियारों की एक महंगी होड़ में फंस जाते हैं। यह अविश्वास और अनिश्चितता का परिणाम है, जहाँ एक पक्ष की सुरक्षा दूसरे की असुरक्षा का कारण बनती है, जिससे शांति के प्रयास विफल हो सकते हैं।

126. (D) आदर्शवादी विचार और अंतर्राष्ट्रीय कानून।
युद्ध की रोकथाम और उसके उन्मूलन के लिए सामूहिक विधिक प्रयास करना आदर्शवादी परंपरा की प्रमुख विशेषता है। यह विचारधारा मानती है कि केवल शक्ति संतुलन से शांति नहीं आ सकती, बल्कि इसके लिए राष्ट्रों के बीच एक साझा कानूनी ढांचा और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की सक्रिय भूमिका आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय कानून राज्यों के आचरण के लिए नियम निर्धारित करता है और सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था एक देश के विरुद्ध आक्रमण को सभी के विरुद्ध मानती है। यह विधिक और संस्थागत दृष्टिकोण बल प्रयोग के स्थान पर न्याय और नियम-आधारित व्यवस्था की स्थापना पर बल देता है।

127. (A) निर्णय-प्रक्रिया दृष्टिकोण
निर्णय-प्रक्रिया दृष्टिकोण यह स्पष्ट करता है कि राज्य के भीतर मौजूद विभिन्न विभागों और व्यक्तियों के बीच के मतभेद विदेश नीति को प्रभावित करते हैं। जब विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और गुप्तचर एजेंसियां अलग-अलग राय रखती हैं, तो अंतिम निर्णय अक्सर उनके बीच की आंतरिक राजनीति और सौदेबाजी का परिणाम होता है। यह स्थिति दर्शाती है कि राज्य कोई 'ब्लैक बॉक्स' नहीं है जो सदैव एकमत होकर निर्णय लेता है। इसके बजाय, नीति निर्माण एक आंतरिक और जटिल प्रक्रिया है जहाँ सूचनाओं के प्रवाह और संस्थागत स्वार्थों का गहरा प्रभाव पड़ता है, जो इस दृष्टिकोण का मूल मंत्र है।

128. (A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
शीतयुद्ध के दौरान विश्व एक द्विध्रुवीय व्यवस्था में विभाजित था, जहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ दो मुख्य शक्ति केंद्र थे। ऐसी स्थिति में राज्यों के लिए अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने का सबसे सरल मार्ग किसी एक महाशक्ति के गठबंधन में शामिल होना था। गठबंधन के माध्यम से छोटे राज्यों को महाशक्ति का संरक्षण प्राप्त होता था, जबकि महाशक्तियों को अपना प्रभाव बढ़ाने का अवसर मिलता था। सुरक्षा की यह खोज ही नाटो और वारसॉ पैक्ट जैसे सैन्य समूहों के गठन का मुख्य कारण बनी। अतः कारण अभिकथन के पीछे के रणनीतिक तर्क को सटीक रूप से स्पष्ट करता है।

129. (C) युद्ध की एकपक्षीय घोषणा।
कूटनीति अनिवार्य रूप से शांतिपूर्ण साधनों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रबंधित करने की कला है। इसमें वार्ता करना, राष्ट्रीय हितों का प्रतिनिधित्व करना और सूचना एकत्र करना शामिल है ताकि संघर्षों को बातचीत से सुलझाया जा सके। युद्ध की एकपक्षीय घोषणा कूटनीति का अंत और बल प्रयोग की शुरुआत को दर्शाती है, इसलिए इसे कूटनीतिक गतिविधि नहीं माना जा सकता। कूटनीति का पूरा उद्देश्य ही युद्ध को टालना और बिना रक्तपात के अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना है। जब कोई राज्य युद्ध की घोषणा करता है, तो वह कूटनीतिक सीमाओं को पार कर प्रत्यक्ष सैन्य संघर्ष में प्रवेश कर जाता है।

130. (A) अंतर्राष्ट्रीय कानून
अंतर्राष्ट्रीय कानून का यह बुनियादी सिद्धांत है कि सभी राज्य, चाहे वे आकार, जनसंख्या या शक्ति में कितने भी भिन्न हों, कानून की दृष्टि में समान संप्रभुता रखते हैं। यह 'संप्रभु समानता' का सिद्धांत संयुक्त राष्ट्र चार्टर का भी आधार है। यह सुनिश्चित करता है कि छोटे राष्ट्रों के पास भी वही कानूनी अधिकार और दर्जा हो जो बड़े राष्ट्रों के पास है। यद्यपि वास्तविक राजनीति में शक्ति का प्रभाव अधिक होता है, लेकिन विधिक रूप से यह समानता राज्यों के बीच न्यायपूर्ण संबंधों और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के लिए एक आवश्यक ढांचा प्रदान करती है।

131. (D) कैसे तर्कसंगत निर्णय सामूहिक रूप से उप-इष्टतम परिणाम की ओर ले जा सकते हैं।
खेल सिद्धांत में 'कैदी की दुविधा' यह दर्शाती है कि जब दो पक्ष एक-दूसरे पर भरोसा नहीं करते, तो वे अपने व्यक्तिगत

Downloaded from www.pdf.tube

गया। चूँकि दोनों पक्ष परमाणु हथियारों से लैस थे, इसलिए उन्हें पता था कि प्रत्यक्ष युद्ध का परिणाम पूर्ण विनाश होगा। इसी 'ठंडे' तनाव ने पूरी दुनिया को दशकों तक भय के साये में रखा, जबकि प्रत्यक्ष 'गर्म' युद्ध को चतुराई से टाल दिया गया।

166. (D) शस्त्रों की दौड़
शस्त्रों की दौड़ विवादों को सुलझाने का शांतिपूर्ण साधन नहीं है, बल्कि यह तनाव और अविश्वास को बढ़ाने वाली एक खतरनाक सैन्य प्रतिस्पर्धा है। वार्ता, मध्यस्थता और अधिनिर्णय कूटनीति और कानून के ऐसे उपकरण हैं जो बिना हिंसा के समाधान निकालने का प्रयास करते हैं। इसके विपरीत, जब राष्ट्र हथियारों का संचय करते हैं, तो वे भविष्य में होने वाले युद्ध की तैयारी कर रहे होते हैं, जिससे शांति की संभावना कम हो जाती है। शस्त्रों की होड़ अक्सर सुरक्षा दुविधा पैदा करती है, जहाँ राष्ट्र अधिक सुरक्षित होने के प्रयास में वास्तव में अधिक असुरक्षित और युद्ध के निकट हो जाते हैं।

167. (C) लोकतंत्र का प्रसार और अंतर्राष्ट्रीय कानून का सुदृढ़ीकरण।
आदर्शवादी दृष्टिकोण का यह दृढ़ मत है कि युद्ध की जड़ें अधिनायकवादी व्यवस्थाओं और अराजक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में छिपी हैं। उनका तर्क है कि लोकतांत्रिक देश आमतौर पर आपस में युद्ध नहीं करते क्योंकि वहां जनता की सहमति और संस्थागत नियंत्रण होता है। इसलिए, दुनिया भर में लोकतंत्र को बढ़ावा देकर और एक मजबूत अंतर्राष्ट्रीय विधिक ढांचा तैयार करके युद्धों को स्थायी रूप से रोका जा सकता है। सामूहिक सुरक्षा और नियम-आधारित व्यवस्था ही वह एकमात्र मार्ग है जिससे राष्ट्रों के बीच संघर्ष को समाप्त कर एक न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण वैश्विक समाज की स्थापना की जा सकती है।

168. (D) दूसरों को प्रभावित करने की अपनी क्षमता बढ़ा सकता है।
अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति के अधिग्रहण का अर्थ है उन सभी संसाधनों, कौशलों और क्षमताओं को संचित करना जिनसे एक राष्ट्र अन्य राज्यों के व्यवहार को अपने अनुकूल बना सके। शक्ति केवल दूसरों पर विजय पाने के लिए नहीं, बल्कि अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने और वैश्विक व्यवस्था में अपनी आवाज को वजन देने के लिए आवश्यक है। इसमें आर्थिक मजबूती, सैन्य आधुनिकता, कूटनीतिक प्रभाव और सांस्कृतिक आकर्षण को बढ़ाना शामिल है। एक शक्तिशाली राज्य अधिक स्वायत्तता के साथ कार्य कर सकता है और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी शर्तों पर सौदेबाजी करने में सक्षम होता है।

169. (A) शक्ति का उपयोग करने की लागत, भौतिक और प्रतिष्ठा दोनों के संदर्भ में, एक महत्वपूर्ण सीमा हो सकती है।
शक्ति का प्रयोग कभी भी मुफ्त नहीं होता। प्रत्येक सैन्य कार्रवाई या कूटनीतिक दबाव के साथ भारी आर्थिक लागत और सैनिकों की जान जाने का जोखिम जुड़ा होता है। इसके अलावा, अनुचित शक्ति प्रदर्शन से किसी राष्ट्र की वैश्विक प्रतिष्ठा को गहरा धक्का लग सकता है और उसे अन्य देशों के विरोध का सामना करना पड़ सकता है। यह 'प्रतिष्ठा संबंधी लागत' भविष्य में उसके प्रभाव को कम कर सकती है। इसलिए, बुद्धिमान नेतृत्व सदैव शक्ति के उपयोग से पहले उसके संभावित लाभों और भारी लागतों के बीच तुलना करता है, जो वास्तव में शक्ति पर एक प्रभावी सीमा है।

170. (D) 1, 2 और 3
अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन अत्यंत व्यापक है और इसे समझने के लिए विभिन्न सैद्धांतिक ढांचे विकसित किए गए हैं। यथार्थवाद और आदर्शवाद शक्ति बनाम नैतिकता की पारंपरिक बहस को प्रस्तुत करते हैं। व्यवस्था और खेल सिद्धांत वैश्विक संरचना और रणनीतिक निर्णयों के वैज्ञानिक विश्लेषण पर जोर देते हैं। संचार और निर्णय-प्रक्रिया दृष्टिकोण सूचना के प्रवाह और नीति निर्माण की आंतरिक जटिलताओं का सूक्ष्म अध्ययन करते हैं। ये सभी दृष्टिकोण मिलकर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विभिन्न आयामों—जैसे सुरक्षा, सहयोग, संरचना और मानवीय कारक—को गहराई से समझने के लिए एक संपूर्ण शैक्षणिक आधार प्रदान करते हैं।

171. (D) हस्तक्षेप का उपयोग, जो अक्सर जातीय विवादों से जुड़ा होता है।
जब कोई राज्य किसी अन्य देश में रहने वाले अपने सजातीय या सांस्कृतिक समूह की रक्षा का दावा करके वहां सेना भेजता है, तो यह 'जातीय आधार पर हस्तक्षेप' का उदाहरण है। यद्यपि इसे अक्सर मानवीय आधार पर उचित ठहराया जाता है, लेकिन यह मूलतः दूसरे राष्ट्र की संप्रभुता का उल्लंघन होता है। ऐसे हस्तक्षेप अक्सर क्षेत्रीय तनाव को बढ़ाते हैं और गृहयुद्धों को अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों में बदल देते हैं। यह दर्शाता है कि कैसे जातीय पहचान और राष्ट्रीय सीमाएं आपस में टकराती हैं, जिससे कूटनीतिक और सैन्य संकट उत्पन्न होता है। यह आधुनिक युद्धों की एक प्रमुख विशेषता है।

172. (B) तर्कसंगत अभिनेता हैं जो अपने विकल्पों की लागत और लाभों की गणना करते हैं।
खेल सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक ऐसी रणनीतिक स्थिति के रूप में देखता है जहाँ राज्य कोई भी कदम उठाने से पहले उसके संभावित परिणामों का सूक्ष्म विश्लेषण करते हैं। इसकी मुख्य धारणा यह है कि राष्ट्र भावुक होकर नहीं, बल्कि ठंडे दिमाग से अपने स्वार्थ को अधिकतम करने के लिए कार्य करते हैं। वे यह अनुमान लगाते हैं कि उनके निर्णय पर अन्य देशों की क्या प्रतिक्रिया होगी और उस स्थिति में उन्हें कितना लाभ या हानि होगी। यह दृष्टिकोण राज्यों के व्यवहार को अधिक पूर्वानुमानित बनाने और जटिल वैश्विक समस्याओं को गणितीय मॉडलों के माध्यम से समझने में सहायता करता है।

173. (C) एकमात्र प्रमुख शक्ति, संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रभुत्व।
शीतयुद्ध की समाप्ति के बाद सोवियत संघ के पतन से वह द्विध्रुवीय संतुलन समाप्त हो गया जिसने दशकों तक विश्व राजनीति को नियंत्रित किया था। इसके परिणामस्वरूप उभरे काल को 'एकध्रुवीय क्षण' कहा गया क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका सैन्य, आर्थिक और वैचारिक रूप से दुनिया की एकमात्र बेजोड़ शक्ति बन गया था। इस व्यवस्था में वैश्विक एजेंडा काफी हद तक अमेरिका की नीतियों और प्राथमिकताओं से प्रभावित रहा। हालांकि, यह स्थिति स्थायी नहीं थी, लेकिन इसने 20वीं

NODIA

140. (D) 1, 2 और 3
यथार्थवादी सिद्धांत के ये तीनों स्तंभ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की एक संघर्षपूर्ण छवि प्रस्तुत करते हैं। यह मानता है कि संप्रभु राज्य ही विश्व राजनीति के मुख्य अभिनेता हैं जो एक ऐसी अराजक व्यवस्था में रहते हैं जहाँ कोई विश्व सरकार नहीं है। इस असुरक्षित वातावरण में, प्रत्येक राज्य का प्राथमिक उद्देश्य अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना और शक्ति बढ़ाना होता है। ये धारणाएं यह स्पष्ट करती हैं कि क्यों राष्ट्र सदैव सैन्य मजबूती और शक्ति संतुलन की होड़ में लगे रहते हैं। यथार्थवाद के अनुसार, शक्ति ही वह एकमात्र साधन है जिसके माध्यम से राज्य इस प्रतिस्पर्धी विश्व में जीवित रह सकते हैं।

141. (A) शीतयुद्ध के दौरान तटस्थ रहना चाहते थे।
गुटनिरपेक्ष आंदोलन उन नव-स्वतंत्र और विकासशील राष्ट्रों का समूह था जिन्होंने शीतयुद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका या सोवियत संघ के नेतृत्व वाले किसी भी सैन्य गुट में शामिल न होने का निर्णय लिया। इनका मुख्य उद्देश्य महाशक्तियों की प्रतिद्वंद्विता से दूर रहकर अपनी स्वतंत्र विदेश नीति और संप्रभुता को सुरक्षित रखना था। तटस्थता का अर्थ यहाँ निष्क्रियता नहीं था, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर गुण-दोष के आधार पर निष्पक्ष निर्णय लेना और शांति को बढ़ावा देना था। यह आंदोलन वैश्विक राजनीति में एक तीसरे विकल्प के रूप में उभरा जिसने उपनिवेशवाद और नस्लवाद का कड़ा विरोध किया।

142. (D) संधि
संधि दो या दो से अधिक संप्रभु राज्यों के बीच संपन्न एक औपचारिक और लिखित समझौता है जो अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा शासित होता है। यह राज्यों के बीच अधिकारों और कर्तव्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है और सहयोग का एक विधिक ढांचा प्रदान करता है। संधियाँ व्यापार, सीमा सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण या सैन्य गठबंधन जैसे विविध विषयों पर हो सकती हैं। जब राज्य किसी संधि पर हस्ताक्षर और उसका अनुसमर्थन करते हैं, तो वे उसके प्रावधानों का पालन करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य हो जाते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में व्यवस्था और पूर्वानुमान सुनिश्चित करने का सबसे विश्वसनीय उपकरण है।

143. (B) अंतः-राज्यीय या गृहयुद्ध
जब सशस्त्र संघर्ष किसी एक ही देश की सीमाओं के भीतर वहां की सरकार और किसी संगठित विद्रोही समूह या विभिन्न समुदायों के बीच होता है, तो उसे अंतः-राज्यीय युद्ध या गृहयुद्ध कहा जाता है। ये संघर्ष अक्सर राजनीतिक सत्ता, क्षेत्रीय स्वायत्तता या जातीय और धार्मिक मतभेदों के कारण उत्पन्न होते हैं। गृहयुद्ध किसी देश की सामाजिक और आर्थिक संरचना को गहराई से नुकसान पहुँचाते हैं और अक्सर पड़ोसी राज्यों को भी अस्थिर कर देते हैं। आधुनिक युग में, राज्यों के बीच होने वाले युद्धों की तुलना में ऐसे आंतरिक संघर्षों की संख्या और विभीषिका में काफी वृद्धि देखी गई है।

144. (C) एक संधि जो वायुमंडल में परमाणु हथियारों के परीक्षण पर प्रतिबंध लगाती है।
शस्त्र नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य हथियारों की प्रतिस्पर्धा को विनियमित करना और युद्ध के जोखिमों को कम करना है। आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि जैसे समझौते इसी का उत्कृष्ट उदाहरण हैं, क्योंकि ये हथियारों के अंधाधुंध विकास और परीक्षण पर सीमाएं लगाते हैं। यह पूर्ण निरस्त्रीकरण नहीं है, बल्कि हथियारों के प्रबंधन की एक रणनीति है ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता बनी रहे और पर्यावरण की रक्षा हो सके। ऐसे समझौते राष्ट्रों के बीच विश्वास बढ़ाने और परमाणु युद्ध की संभावना को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक कदम माने जाते हैं, जो सुरक्षा को अधिक पूर्वानुमानित बनाते हैं।

145. (A) मानवीय प्रगति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की संभावना।
यथार्थवाद जहाँ संघर्ष को अपरिहार्य मानता है, वहीं आदर्शवाद मानवीय विवेक और प्रगति में गहरा विश्वास रखता है। आदर्शवादी दृष्टिकोण यह मानता है कि राष्ट्र अपने संकीर्ण हितों से ऊपर उठकर साझा लक्ष्यों के लिए सहयोग कर सकते हैं। इस विचारधारा के अनुसार, युद्ध कोई शाश्वत सत्य नहीं है, बल्कि इसे लोकतंत्र के विस्तार, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की मजबूती और नैतिक मूल्यों के पालन के माध्यम से समाप्त किया जा सकता है। यह मानव स्वभाव की अच्छाई और तर्कसंगतता पर आधारित एक उज्जवल भविष्य की परिकल्पना करता है, जहाँ शक्ति के स्थान पर कानून का शासन सर्वोपरि होता है।

146. (B) संचार और निर्णय-प्रक्रिया दृष्टिकोण
जब युद्ध का विश्लेषण नेताओं की गलत धारणाओं, सूचनाओं के त्रुटिपूर्ण प्रवाह और मनोवैज्ञानिक पूर्वाग्रहों के आधार पर किया जाता है, तो वह संचार और निर्णय-प्रक्रिया दृष्टिकोण के दायरे में आता है। ये सिद्धांत मानते हैं कि युद्ध अक्सर केवल शक्ति के संघर्ष से नहीं, बल्कि इस बात से शुरू होते हैं कि निर्णय लेने वाले दूसरे पक्ष के इरादों को कैसे समझते हैं। यदि संदेशों की व्याख्या गलत हो या सूचना अधूरी हो, तो एक छोटा सा विवाद भी बड़े युद्ध का रूप ले सकता है। यह विश्लेषण राज्य को केवल एक निर्जीव इकाई नहीं, बल्कि मानवीय संवेदनाओं से प्रभावित व्यवस्था के रूप में देखता है।

147. (D) विदेशी हस्तक्षेप का विरोध करने वाला घरेलू जनमत।
किसी राज्य की शक्ति पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होती, बल्कि वह आंतरिक और बाहरी सीमाओं से बंधी होती है। घरेलू जनमत शक्ति के उपयोग पर एक अत्यंत प्रभावशाली अंकुश है। यदि देश की जनता किसी युद्ध या विदेशी हस्तक्षेप के विरुद्ध है, तो लोकतांत्रिक नेतृत्व के लिए अपनी सैन्य शक्ति का प्रयोग करना कठिन हो जाता है। जनमत का दबाव संसाधनों के आवंटन और नीतियों की वैधता को प्रभावित करता है। इसके अतिरिक्त, वियतनाम युद्ध जैसे ऐतिहासिक उदाहरण दर्शाते हैं कि कैसे आंतरिक विरोध एक शक्तिशाली सेना को भी पीछे हटने पर मजबूर कर सकता है। अतः जनता का समर्थन शक्ति का एक अनिवार्य आधार है।

148. (A) बर्लिन की दीवार का गिरना।
1989 में बर्लिन की दीवार का ढहना शीतयुद्ध के अंत का सबसे शक्तिशाली और भावनात्मक प्रतीक माना जाता है। इसने न केवल जर्मनी के विभाजन को समाप्त करने की शुरुआत की, बल्कि पूर्वी यूरोप में सोवियत प्रभाव और साम्यवादी शासन के पतन को भी रेखांकित किया। यह घटना उस 'आयरन कर्टन' के

Click Here to Buy book on Amazon

जब कोई देश अपनी फिल्मों, शिक्षा व्यवस्था या लोकतांत्रिक आदर्शों के जरिए वैश्विक मंच पर अपनी सकारात्मक छवि बनाता है, तो वह वास्तव में मृदु शक्ति का उपयोग कर रहा होता है। यह तकनीक राज्यों को बल प्रयोग के बिना अपने राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में अपना सम्मान और प्रभाव बढ़ाने में सक्षम बनाती है। यह आधुनिक कूटनीति का एक अत्यंत प्रभावी उपकरण है।

98. (A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
यथार्थवादी सिद्धांत अक्सर राज्य को एक ही दिशा में सोचने वाले 'एकात्मक अभिनेता' के रूप में देखता है, लेकिन निर्णय-प्रक्रिया दृष्टिकोण इस सरलीकरण को अस्वीकार करता है। इसका मानना है कि विदेश नीति कोई स्वचालित परिणाम नहीं है, बल्कि यह सरकार के भीतर मौजूद विभिन्न विभागों और व्यक्तियों के बीच होने वाले निरंतर संघर्ष और समझौतों की उपज है। यह दृष्टिकोण इस जटिलता को उजागर करता है कि कैसे आंतरिक मतभेद और सामूहिक विचार-विमर्श अंतिम निर्णय को प्रभावित करते हैं। अतः कारण अभिकथन के पीछे के तर्क को पूरी तरह स्पष्ट करता है।

99. (B) अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानदंड
किसी भी राज्य की शक्ति पूर्णतः निरंकुश नहीं हो सकती क्योंकि वह अंतर्राष्ट्रीय कानून, संधियों और स्थापित वैश्विक मानदंडों द्वारा सीमित होती है। इन नियमों का उल्लंघन करने पर किसी देश को कूटनीतिक अलगाव, आर्थिक प्रतिबंधों या सामूहिक सैन्य कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मानदंड राज्यों के व्यवहार के लिए एक नैतिक और विधिक सीमा रेखा तय करते हैं। यद्यपि शक्तिशाली राज्य कभी-कभी इन नियमों की अनदेखी करते हैं, फिर भी विश्व समुदाय का दबाव और वैधता खोने का डर उनकी शक्ति के स्वेच्छाचारी प्रयोग पर एक प्रभावी अंकुश के रूप में कार्य करता है।

100. (B) उदारवाद या यूटोपियनवाद
अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आदर्शवादी दृष्टिकोण को अक्सर 'उदारवाद' कहा जाता है क्योंकि यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता, लोकतंत्र और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के उदारवादी मूल्यों पर आधारित है। कभी-कभी आलोचक इसे 'यूटोपियनवाद' भी कहते हैं क्योंकि यह यथार्थ की कड़वाहट के बजाय एक आदर्श और युद्धमुक्त विश्व की कल्पना करता है। यह विचारधारा मानती है कि मनुष्य स्वभाव से अच्छा है और सही संस्थानों के माध्यम से शांतिपूर्ण समाज का निर्माण संभव है। यह शक्ति की राजनीति के स्थान पर कानून और नैतिकता को अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का नियामक बनाने की वकालत करता है।

101. (A) संचार दृष्टिकोण
संचार दृष्टिकोण यह विश्लेषण करता है कि कैसे सूचनाओं का आदान-प्रदान और उनकी व्याख्या राज्यों के व्यवहार को प्रभावित करती है। यह दृष्टिकोण इस बात पर जोर देता है कि वास्तविक खतरे से अधिक महत्वपूर्ण वह 'धारणा' है जो एक देश दूसरे के प्रति रखता है। यदि संचार स्पष्ट नहीं है, तो गलत धारणाएं और अविश्वास उत्पन्न हो सकते हैं, जिससे रक्षात्मक कदम भी आक्रामक प्रतीत होने लगते हैं। यही स्थिति अक्सर अनपेक्षित संघर्षों को जन्म देती है। अतः अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शांति बनाए रखने के लिए सूचना का सटीक प्रवाह और पारदर्शी संचार अत्यंत आवश्यक है।

102. (C) किसी मिशन या विश्वासों के समूह के आधार पर अपने कार्यों को उचित ठहराते हैं।
विचारधारा राज्यों को एक ऐसा वैचारिक ढांचा प्रदान करती है जिसके माध्यम से वे अपनी नीतियों और कार्यों को नैतिक आधार पर सही सिद्ध करते हैं। जब कोई देश यह दावा करता है कि वह लोकतंत्र की रक्षा के लिए या किसी विशिष्ट राजनीतिक दर्शन के प्रसार के लिए हस्तक्षेप कर रहा है, तो वहां विचारधारा की भूमिका अत्यंत स्पष्ट होती है। यह घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय जनमत को एकजुट करने का एक शक्तिशाली उपकरण है। विचारधारा केवल विचारों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय हितों को एक मिशन के रूप में परिभाषित करने और उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रेरक शक्ति प्रदान करती है।

103. (B) नीति का एक साधन है जिसका उपयोग राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है।
प्रसिद्ध युद्ध दार्शनिक क्लॉज़विट्ज़ के अनुसार, युद्ध कोई निरर्थक हिंसा नहीं है, बल्कि यह 'अन्य साधनों द्वारा राजनीति का विस्तार' है। इसका अर्थ है कि राज्य युद्ध का सहारा केवल तभी लेते हैं जब वे अपने विशिष्ट राजनीतिक उद्देश्यों को कूटनीति के माध्यम से प्राप्त नहीं कर पाते। युद्ध एक रणनीतिक उपकरण है जिसका उपयोग राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए किया जाता है। यद्यपि इसके परिणाम विनाशकारी होते हैं, परंतु इसकी योजना और संचालन सदैव किसी न किसी राजनीतिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है।

104. (A) P-3, Q-1, R-2, S-4
द्विध्रुवीयता शीतयुद्ध की उस व्यवस्था को दर्शाती है जहाँ विश्व दो प्रमुख महाशक्तियों के इर्द-गिर्द सिमट गया था। गठबंधन, जैसे नाटो, इस काल के प्रमुख सैन्य समझौते थे जो सामूहिक सुरक्षा के लिए बनाए गए थे। गुटनिरपेक्षता उन राष्ट्रों की नीति थी जो इन दोनों शक्ति गुटों से स्वतंत्र रहकर अपनी स्वायत्तता बनाए रखना चाहते थे। निवारण का अर्थ परमाणु हथियारों के जरिए प्रतिशोध का डर दिखाकर शत्रु को आक्रमण करने से रोकना था। ये चारों अवधारणाएं शीतयुद्ध के जटिल रणनीतिक और राजनीतिक परिदृश्य को पूरी तरह परिभाषित करती हैं।

105. (D) गुटनिरपेक्षता
गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन करने वाला राज्य स्वेच्छा से किसी भी महाशक्ति के नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन का हिस्सा बनने से इनकार कर देता है। इसका मुख्य उद्देश्य अपनी विदेश नीति को स्वतंत्र रखना और वैश्विक मुद्दों पर बिना किसी बाहरी दबाव के निर्णय लेना है। यह किसी भी गुट की प्रतिद्वंद्विता में शामिल न होकर राष्ट्रों के बीच शांतिपूर्ण सहयोग और समानता पर बल देता है। यह विशेष रूप से शीतयुद्ध के दौरान नव-स्वतंत्र राष्ट्रों के लिए अपनी पहचान और संप्रभुता की रक्षा करने का एक प्रभावी कूटनीतिक मार्ग था, जो आज भी प्रासंगिक है।

NODIA

157. (D) संप्रभुता
संप्रभुता का अर्थ है कि एक राज्य अपने भौगोलिक क्षेत्र के भीतर सर्वोच्च सत्ता रखता है और किसी भी बाहरी शक्ति के अधीन नहीं है। इस अधिकार का दूसरा पक्ष 'गैर-हस्तक्षेप का कर्तव्य' है। यदि सभी राज्य संप्रभु हैं, तो किसी भी राज्य को दूसरे के घरेलू मामलों में बलपूर्वक प्रवेश या दबाव डालने का कानूनी अधिकार नहीं है। यह सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में राज्यों की स्वतंत्रता और समानता को सुरक्षित रखता है। संप्रभुता का सम्मान करना ही वह नींव है जिस पर राष्ट्रों के बीच शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पूरा ढांचा टिका हुआ है।

158. (C) A सत्य है लेकिन R असत्य है।
प्रत्येक राज्य की विदेश नीति का प्राथमिक लक्ष्य वास्तव में अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित और प्रोत्साहित करना होता है, अतः अभिकथन सत्य है। हालांकि, कारण गलत है क्योंकि राष्ट्रीय हित कोई वस्तुनिष्ठ या सार्वभौमिक सूची नहीं है। विभिन्न राज्यों के हित उनके भूगोल, संसाधनों, इतिहास और विचारधारा के आधार पर भिन्न-भिन्न होते हैं। यहाँ तक कि एक ही राज्य के भीतर, अलग-अलग सरकारें राष्ट्रीय हित को अलग तरह से परिभाषित कर सकती हैं। यह एक निरंतर विकसित होने वाली और विवादित अवधारणा है जिसे नीति निर्माता अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार तय करते हैं।

159. (C) परमाणु युद्ध
परमाणु युद्ध वह संघर्ष है जिसमें परमाणु विखंडन या संलयन की प्रक्रिया से उत्पन्न अत्यधिक विनाशकारी हथियारों का उपयोग किया जाता है। इन हथियारों की मारक क्षमता पारंपरिक बमों से हजारों गुना अधिक होती है और इनका प्रभाव केवल तात्कालिक विनाश तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह विकिरण के माध्यम से आने वाली पीढ़ियों और पर्यावरण को भी नष्ट कर देता है। इसकी भयावहता के कारण इसे 'मानवता के अस्तित्व के लिए खतरा' माना जाता है। शीतयुद्ध के दौरान इस प्रकार के युद्ध की संभावना ने ही निवारण के सिद्धांतों और वैश्विक शांति के नए आयामों को जन्म दिया।

160. (A) आदर्शवादी
आदर्शवादी दृष्टिकोण यह मानता है कि विश्व में शांति केवल शक्ति संतुलन से नहीं, बल्कि साझा नैतिक मानदंडों और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रसार से ही स्थायी रूप से स्थापित हो सकती है। यह विचारधारा इस बात पर जोर देती है कि जब राष्ट्र एक जैसे संस्थानों और कानूनों के तहत कार्य करते हैं, तो उनके बीच सहयोग की संभावना बढ़ जाती है। आदर्शवादियों के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और विधिक ढांचे अराजक व्यवस्था को एक नियम-आधारित समुदाय में बदल सकते हैं। यह दृष्टिकोण संघर्ष के स्थान पर तर्कसंगत संवाद और संस्थागत सहयोग को वैश्विक राजनीति का केंद्र मानता है।

161. (D) राष्ट्रीय हित का निर्धारण।
राष्ट्रीय हित का निर्धारण वह रणनीतिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी देश का नेतृत्व यह तय करता है कि उसकी सुरक्षा, समृद्धि और वैश्विक स्थिति के लिए कौन से लक्ष्य अनिवार्य हैं। इसमें राष्ट्र के दीर्घकालिक मूल्यों और तत्कालीन चुनौतियों के बीच संतुलन बिठाया जाता है। यह निर्धारण ही विदेश नीति की पूरी दिशा तय करता है और बताता है कि राज्य को किन देशों के साथ दोस्ती करनी चाहिए और किन खतरों से सावधान रहना चाहिए। यह प्रक्रिया निरंतर चलने वाली और गतिशील है, जो बदलते वैश्विक परिदृश्य और आंतरिक जरूरतों के साथ स्वयं को अनुकूलित करती रहती है।

NODIA

162. (B) वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक मानदंडों के अनुरूप होने के लिए राज्यों पर बढ़ता दबाव।
वैश्वीकरण ने राज्यों को एक ऐसी एकीकृत व्यवस्था में बांध दिया है जहाँ उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मानकों और नियमों का पालन करना अनिवार्य हो गया है। अब कोई भी देश विश्व व्यापार संगठन जैसे संस्थानों के नियमों या वैश्विक मानवाधिकार मानदंडों की पूरी तरह अनदेखी नहीं कर सकता। आर्थिक परस्पर निर्भरता के कारण राष्ट्रों को अपनी घरेलू नीतियों को वैश्विक बाजार की माँगों के अनुसार ढालना पड़ता है। यद्यपि राज्य अभी भी संप्रभु हैं, लेकिन उनकी कार्य करने की स्वायत्तता अब पहले की तुलना में अधिक बाहरी दबावों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकताओं से सीमित हो गई है।

163. (C) निर्णय-प्रक्रिया दृष्टिकोण
निर्णय-प्रक्रिया दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मानवीय अभिनेताओं के निर्णयों के परिणाम के रूप में देखता है। यह इस बात का गहराई से अध्ययन करता है कि व्यक्तिगत नेताओं के व्यक्तित्व, उनकी शिक्षा, विश्वास और संकट के समय उनकी मानसिक स्थिति विदेश नीति को कैसे प्रभावित करती है। यह मानता है कि राज्य कोई बेजान मशीन नहीं है, बल्कि उसके निर्णय उन लोगों द्वारा लिए जाते हैं जिनके अपने पूर्वाग्रह और सोचने के तरीके होते हैं। इसलिए, किसी भी ऐतिहासिक घटना को समझने के लिए उन व्यक्तियों के मानस को समझना आवश्यक है जिन्होंने वह निर्णय लिया था।

164. (B) P-4, Q-1, R-2, S-3
संप्रभुता राज्य के अपने क्षेत्र के भीतर सर्वोच्च अधिकार को दर्शाती है, जबकि हस्तक्षेप किसी अन्य राष्ट्र के मामलों में बलपूर्वक प्रवेश का प्रतीक है। संधि दो या दो से अधिक राज्यों के बीच होने वाला एक औपचारिक लिखित समझौता है जो उनके संबंधों को व्यवस्थित करता है। शांतिपूर्ण समाधान उन विधियों का समूह है जिनके माध्यम से विवादों को बिना किसी युद्ध या हिंसा के सुलझाया जाता है। ये चारों अवधारणाएं अंतर्राष्ट्रीय कानून के मूल स्तंभ हैं, जो वैश्विक व्यवस्था में राज्यों के अधिकारों, दायित्वों और संघर्ष समाधान के विधिक ढांचे को स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हैं।

165. (B) दोनों महाशक्तियों के बीच कोई प्रत्यक्ष बड़े पैमाने पर युद्ध नहीं हुआ था।
'शीतयुद्ध' शब्द उस स्थिति को दर्शाता है जहाँ शत्रुता और तनाव चरम पर थे, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ की सेनाओं के बीच कभी भी सीधे आमने-सामने का युद्ध नहीं हुआ। इसके बजाय, यह संघर्ष परोक्ष युद्धों, जासूसी, मनोवैज्ञानिक प्रचार और शस्त्रों की होड़ के माध्यम से लड़ा

हित में ऐसे विकल्प चुनते हैं जो सामूहिक रूप से दोनों के लिए हानिकारक होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, यह स्थिति अक्सर शस्त्रों की दौड़ में दिखाई देती है जहाँ दोनों राज्य सहयोग के लाभों को जानते हुए भी अविश्वास के कारण हथियारों पर पैसा खर्च करना जारी रखते हैं। यह मॉडल स्पष्ट करता है कि अराजक व्यवस्था में अविश्वास कैसे राष्ट्रों को ऐसी स्थितियों में धकेलता है जहाँ वे शांति के बजाय असुरक्षा का चुनाव करने पर मजबूर होते हैं।

132. (B) अन्य राज्यों के विरुद्ध बल प्रयोग या उसकी धमकी से बचना।
आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय कानून का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य यह है कि राज्य अपनी विदेश नीति में बल प्रयोग या आक्रमण की धमकी का सहारा न लें। यह सिद्धांत संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 2(4) में निहित है और वैश्विक शांति बनाए रखने का आधार है। राज्यों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने विवादों को केवल शांतिपूर्ण माध्यमों, जैसे वार्ता या मध्यस्थता, से हल करें। यह नियम राज्यों की क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता की रक्षा करता है और अराजकता को नियंत्रित कर एक नियम-आधारित विश्व व्यवस्था की स्थापना में सहयोग प्रदान करता है।

133. (A) कथन I और कथन II दोनों सत्य हैं।
युद्ध के कारणों का विश्लेषण करने पर पता चलता है कि वे अत्यंत विविधतापूर्ण हो सकते हैं। एक ओर, सीमा विवाद, जल संसाधन या तेल भंडार जैसे मूर्त और भौतिक संसाधनों पर नियंत्रण के लिए राष्ट्रों के बीच युद्ध होते हैं। दूसरी ओर, विचारधाराओं के टकराव या गहरी जातीय और सांस्कृतिक शत्रुता जैसे अमूर्त कारक भी संघर्ष का कारण बनते हैं। वास्तव में, अधिकांश युद्ध इन दोनों प्रकार के कारकों के जटिल मिश्रण का परिणाम होते हैं, जहाँ भौतिक स्वार्थों को अक्सर वैचारिक या जातीय भावनाओं का आवरण पहना दिया जाता है।

134. (B) P-2, Q-1, R-4, S-3
वैश्वीकरण आधुनिक युग की बढ़ती हुई वैश्विक परस्पर संबद्धता को दर्शाता है, जबकि शीतयुद्ध दो महाशक्तियों के बीच का एक लंबा वैचारिक और रणनीतिक संघर्ष था। गुटनिरपेक्षता की नीति का मुख्य उद्देश्य इन शक्ति गुटों से स्वतंत्र रहकर स्वायत्त निर्णय लेने की क्षमता बनाए रखना था। निरस्त्रीकरण का सीधा संबंध हथियारों की संख्या में कमी करने या उन्हें पूरी तरह समाप्त करने के प्रयासों से है। ये चारों अवधारणाएं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से लेकर वर्तमान समय तक की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की दिशा और दशा को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण आधार प्रदान करती हैं।

135. (C) राज्य की संप्रभुता और गैर-हस्तक्षेप
संप्रभुता का पारंपरिक सिद्धांत यह मानता है कि राज्य अपने आंतरिक मामलों में पूर्णतः स्वतंत्र है और किसी भी बाहरी शक्ति को हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है। हालांकि, 'मानवीय हस्तक्षेप' की अवधारणा इस विचार को चुनौती देती है। यह तर्क देती है कि यदि कोई राज्य अपनी ही जनता पर नरसंहार या भारी अत्याचार करता है, तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का यह नैतिक उत्तरदायित्व है कि वह मानवता की रक्षा के लिए वहां हस्तक्षेप करे। यह संप्रभुता के अधिकार और मानवाधिकारों की सुरक्षा के बीच एक गहरा संघर्ष पैदा करता है, जो आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय कानून में एक बड़ी बहस का विषय है।

136. (D) शक्ति के अमूर्त तत्व
राष्ट्रीय शक्ति केवल बंदूकों और पैसों तक सीमित नहीं है; इसमें नेतृत्व की गुणवत्ता, कुशल प्रशासन और जनता का मनोबल जैसे अदृश्य तत्व भी शामिल हैं। इन्हें 'अमूर्त तत्व' कहा जाता है क्योंकि इन्हें भौतिक रूप से मापना कठिन है, परंतु वे किसी राष्ट्र की सफलता में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। एक महान नेतृत्व सीमित संसाधनों के बावजूद देश को संकट से निकाल सकता है, जबकि उच्च राष्ट्रीय मनोबल युद्ध के समय सेना को अपार शक्ति प्रदान करता है। ये तत्व दर्शाते हैं कि मानवीय और संगठनात्मक क्षमताएं राष्ट्र की कुल शक्ति का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।

137. (A) व्यवस्था दृष्टिकोण
व्यवस्था दृष्टिकोण यह मानता है कि राज्यों का व्यवहार केवल उनकी अपनी इच्छा का परिणाम नहीं होता, बल्कि यह वैश्विक व्यवस्था की संरचना द्वारा निर्धारित होता है। यह दृष्टिकोण इस बात पर जोर देता है कि शक्ति का वैश्विक वितरण और शक्ति का वितरण यह तय करता है कि राज्य एक-दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। जैसे एक खेल के नियम खिलाड़ियों के व्यवहार को सीमित करते हैं, वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था राज्यों की स्वायत्तता को आकार देती है। यह विश्लेषण राज्य के आंतरिक कारकों के बजाय बाहरी संरचनात्मक दबावों पर अधिक केंद्रित होता है।

138. (B) निवारण
निवारण का मूल तर्क यह है कि यदि आपके पास इतना विनाशकारी हथियार है कि वह शत्रु को पूरी तरह मिटा सकता है, तो शत्रु आक्रमण करने का जोखिम नहीं उठाएगा। यहाँ शांति सहयोग से नहीं, बल्कि 'भयानक प्रतिशोध के भय' से स्थापित होती है। परमाणु हथियारों के संदर्भ में इसे 'परस्पर सुनिश्चित विनाश' की संभावना के रूप में देखा जाता है। निवारण युद्ध को जीतने की रणनीति नहीं है, बल्कि यह शत्रु के मानस में यह बैठाने का प्रयास है कि युद्ध की कीमत उसके संभावित लाभों से कहीं अधिक होगी। यह भय पर आधारित एक रणनीतिक स्थिरता है।

139. (C) घरेलू कारकों और बाहरी अंतर्राष्ट्रीय वातावरण के बीच एक गतिशील अंतःक्रिया है।
राष्ट्रीय हित का निर्धारण कोई एकाकी प्रक्रिया नहीं है। यह एक ओर देश की आंतरिक आवश्यकताओं, जनमत और आर्थिक संसाधनों से प्रभावित होता है, और दूसरी ओर वैश्विक स्तर पर मौजूद खतरों, अवसरों और अन्य राज्यों के व्यवहार से आकार लेता है। नीति निर्माताओं को इन दोनों के बीच निरंतर संतुलन बनाए रखना पड़ता है। जैसे-जैसे दुनिया बदलती है और देश के भीतर नई सरकारें आती हैं, राष्ट्रीय हित की परिभाषा और उसे प्राप्त करने के तरीके भी बदलते रहते हैं। यह एक अत्यंत जटिल और निरंतर चलने वाली राजनीतिक एवं कूटनीतिक प्रक्रिया है।

Downloaded from www.pdf.tube

सदी के अंत और 21वीं सदी की शुरुआत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की दिशा और स्वरूप को गहराई से प्रभावित किया।

174. (D) निर्णय-प्रक्रिया सिद्धांत : राज्य एक अखंड, एकात्मक अभिनेता के रूप में
निर्णय-प्रक्रिया सिद्धांत की मुख्य विशेषता ही यह है कि वह राज्य को एक अखंड या एकात्मक अभिनेता मानने के यथार्थवादी विचार को नकारता है। इसके विपरीत, यह मानता है कि राज्य के भीतर अनेक उप-इकाइयां, मंत्रालय और व्यक्ति होते हैं जो मिलकर नीति बनाते हैं। यथार्थवाद राज्य-केंद्रित है और आदर्शवाद मानव स्वभाव को लेकर आशावादी है, जबकि व्यवस्था सिद्धांत वैश्विक संरचना को प्राथमिकता देता है। अतः विकल्प D गलत सुमेलित है क्योंकि निर्णय-प्रक्रिया दृष्टिकोण राज्य की आंतरिक विविधता और जटिलताओं के विश्लेषण पर बल देता है, न कि उसकी एकता पर।

175. (A) अन्य राज्यों के विरुद्ध आक्रामकता से बचने का कर्तव्य।
अंतर्राष्ट्रीय कानून में अधिकार और कर्तव्य एक-दूसरे के पूरक हैं। यदि प्रत्येक राज्य को अस्तित्व और आत्मरक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त है, तो यह आवश्यक है कि सभी राज्य दूसरे के विरुद्ध आक्रामकता न करने के कर्तव्य का पालन करें। आक्रामकता से बचने का यह नियम ही आत्मरक्षा के अधिकार को सार्थक बनाता है। यदि बल प्रयोग पर कोई प्रतिबंध न हो, तो छोटे राज्यों का अस्तित्व सदैव खतरे में रहेगा। अतः यह कानूनी व्यवस्था शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है, जहाँ प्रत्येक राष्ट्र की सुरक्षा दूसरों के द्वारा संयम बरतने के सामूहिक दायित्व पर निर्भर करती है।

176. (B) विचारधारा और संचार
युद्ध के दौरान विचारधारा और संचार का उपयोग अक्सर मनोवैज्ञानिक हथियार के रूप में किया जाता है। जब कोई राज्य अपनी जनता और सेना को युद्ध के लिए प्रेरित करता है, तो वह संचार के माध्यमों से शत्रु को 'अमानवीय' दिखाने का प्रयास करता है। यह वैचारिक प्रचार युद्ध को एक नैतिक मिशन के रूप में प्रस्तुत करता है, जिससे हिंसा के प्रति प्रतिरोध कम हो जाता है। यह प्रक्रिया दर्शाती है कि युद्ध केवल मैदान पर नहीं, बल्कि सूचनाओं और धारणाओं के स्तर पर भी लड़ा जाता है। प्रभावी संचार राष्ट्र के मनोबल को बढ़ा सकता है और शत्रु की छवि बिगाड़ सकता है।

177. (C) गठबंधन
जब कोई राज्य स्वेच्छा से किसी औपचारिक सैन्य समूह, जैसे नाटो, का सदस्य बनता है, तो वह वास्तव में एक 'गठबंधन' में प्रवेश कर रहा होता है। गठबंधन का उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों की सामूहिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है, जहाँ एक पर हमला सभी पर हमला माना जाता है। यह राज्य की सुरक्षा बढ़ाने की एक रणनीतिक प्रक्रिया है, जो उसे अकेले पड़ने के जोखिम से बचाती है। गठबंधन के माध्यम से राष्ट्र अपनी सैन्य क्षमताओं और कूटनीतिक प्रभाव को साझा करते हैं, जिससे वे किसी संभावित शक्तिशाली शत्रु के विरुद्ध एक प्रभावी शक्ति संतुलन स्थापित करने में सफल हो पाते हैं।

178. (D) कथन I असत्य है, लेकिन कथन II सत्य है।
शक्ति केवल टैंकों और विमानों जैसे मूर्त संसाधनों तक सीमित नहीं है, और न ही ये अकेले युद्ध का परिणाम तय करते हैं। कथन II बिल्कुल सही है क्योंकि राष्ट्रीय मनोबल, एकता और नेतृत्व की बुद्धिमत्ता जैसे अमूर्त तत्व ही अक्सर यह तय करते हैं कि उपलब्ध संसाधनों का कितनी प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाएगा। इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहाँ छोटी लेकिन अधिक प्रेरित सेनाओं ने विशाल सैन्य शक्ति को पराजित किया है। अतः शक्ति के विश्लेषण में भौतिक साधनों के साथ-साथ मनोवैज्ञानिक और संगठनात्मक पहलुओं को समझना अत्यंत अनिवार्य है, क्योंकि वे शक्ति को जीवंत बनाते हैं।

179. (B) एक जातीय विवाद।
जातीय विवादों की मूल जड़ पहचान की राजनीति में होती है, जहाँ एक विशिष्ट भाषाई, सांस्कृतिक या धार्मिक समूह अपनी स्वायत्तता या स्वतंत्र राज्य की मांग करता है। यह संघर्ष केवल भौतिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व और सम्मान की रक्षा के लिए लड़ा जाता है। ऐसे विवाद अक्सर उन राष्ट्र-राज्यों की सीमाओं के भीतर उत्पन्न होते हैं जहाँ अल्पसंख्यक समूहों को लगता है कि उनकी पहचान खतरे में है। ये संघर्ष अत्यंत लंबे और कड़वे हो सकते हैं क्योंकि पहचान से जुड़ी भावनाएं समझौते को कठिन बना देती हैं। आधुनिक विश्व में ये अस्थिरता के प्रमुख कारण हैं।

NODIA

180. (A) समझौतों का पालन सद्भावना से किया जाना चाहिए।
'पाक्टा संट सरवेंडा' अंतर्राष्ट्रीय संधि कानून का सबसे मौलिक और प्राचीन सिद्धांत है। इसका सीधा अर्थ है कि जब राज्य स्वेच्छा से किसी संधि पर हस्ताक्षर करते हैं, तो उन्हें उसके प्रावधानों का पालन पूर्ण ईमानदारी और सद्भावना के साथ करना चाहिए। यह सिद्धांत वैश्विक व्यवस्था में विश्वसनीयता का आधार है। यदि राष्ट्र अपनी सुविधा के अनुसार संधियों को तोड़ने लगेंगे, तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और विश्वास का पूरा ढांचा ढह जाएगा। यह नियम राज्यों को उनके विधिक वादों के प्रति जवाबदेह बनाता है और अराजक विश्व में एक प्रकार का विधिक अनुशासन स्थापित करता है।

181. (D) बहुराष्ट्रीय निगम और अंतर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठन।
वैश्वीकरण ने विश्व राजनीति के पारंपरिक 'राज्य-केंद्रित' ढांचे को गहराई से चुनौती दी है। आर्थिक एकीकरण और सूचना क्रांति ने बहुराष्ट्रीय निगमों को इतनी आर्थिक शक्ति प्रदान की है कि वे कई छोटे देशों के बजट से भी बड़े हो गए हैं। साथ ही, मानवाधिकार और पर्यावरण जैसे मुद्दों पर काम करने वाले गैर-सरकारी संगठन अब वैश्विक जनमत को प्रभावित करने और अंतर्राष्ट्रीय नीतियों को आकार देने में राज्यों के साथ खड़े हैं। ये नए अभिनेता सीमाओं के पार कार्य करते हैं और राज्यों की पूर्ण संप्रभुता और निर्णय लेने की क्षमता को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित करते हैं।

182. (B) सोवियत संघ के आंतरिक पतन के कारण शक्ति संतुलन में बदलाव।
यथार्थवादी दृष्टिकोण सदैव शक्ति के वितरण और राज्यों के बीच संतुलन पर ध्यान केंद्रित करता है। यथार्थवादियों

युद्ध केवल संसाधनों के लिए नहीं, बल्कि एक 'महान लक्ष्य' या ईश्वरीय आदेश की पूर्ति के लिए लड़ा जाता है। आधुनिक इतिहास में भी धार्मिक उग्रवाद ने कई क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों को जन्म दिया है, जो दर्शाते हैं कि वैचारिक मतभेद राष्ट्रों और समूहों के बीच संघर्ष का एक अत्यंत शक्तिशाली और खतरनाक आधार हो सकते हैं।

216. (D) शस्त्र नियंत्रण या निरस्त्रीकरण
जब दुनिया के अधिकांश राष्ट्र मिलकर किसी घातक हथियार की श्रेणी पर प्रतिबंध लगाने के लिए संधि करते हैं, तो यह शस्त्र नियंत्रण और निरस्त्रीकरण का एक सफल उदाहरण है। ऐसी संधियों का उद्देश्य मानवता की रक्षा करना और युद्ध के विनाशकारी स्वरूप को सीमित करना होता है। यह दर्शाता है कि संप्रभु राज्य अपने राष्ट्रीय स्वार्थों से ऊपर उठकर वैश्विक सुरक्षा और मानवीय मूल्यों के लिए सामूहिक रूप से कार्य कर सकते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की शक्ति का प्रमाण है, जो विधिक ढांचों के माध्यम से एक सुरक्षित विश्व बनाने की दिशा में राष्ट्रों की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है।

217. (A) राज्य एक एकल, सुसंगत इकाई के रूप में कार्य करता है जो अपने रणनीतिक उद्देश्यों को अधिकतम करने के लिए विकल्प चुनता है।
तर्कसंगत अभिनेता मॉडल यह मानता है कि विदेश नीति निर्माण एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया है जहाँ राज्य एक व्यक्ति की तरह सोचता है और कार्य करता है। इस मॉडल के अनुसार, सरकार के पास स्पष्ट लक्ष्य होते हैं, वह उपलब्ध सभी विकल्पों का विश्लेषण करती है, उनकी लागत और लाभों की गणना करती है, और अंततः उस विकल्प को चुनती है जो उसके राष्ट्रीय हित को सबसे अधिक बढ़ाता है। यह विश्लेषण जटिलताओं को सरल बनाता है और यह मान लेता है कि संकट के समय राज्य पूरी तरह ठंडे दिमाग और तर्क के आधार पर अपने कदम उठाता है, जिससे उसके व्यवहार को समझना आसान हो जाता है।

218. (A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
वैश्वीकरण ने सूचना और संस्कृति के वैश्विक प्रवाह को अभूतपूर्व गति प्रदान की है, जिससे स्थानीय परंपराओं और राष्ट्रीय पहचान के सामने गंभीर चुनौतियाँ उत्पन्न हुई हैं। पश्चिमी मीडिया, उपभोग की आदतों और जीवनशैली का विश्वव्यापी प्रसार सांस्कृतिक समरूपीकरण का भय पैदा करता है, जहाँ विशिष्ट क्षेत्रीय संस्कृतियां धीरे-धीरे अपनी मौलिकता खोने लगती हैं। यह प्रक्रिया कई समाजों में असुरक्षा की भावना पैदा करती है, जिसके परिणामस्वरूप कभी-कभी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की तीव्र प्रतिक्रिया भी देखने को मिलती है। अतः कारण अभिकथन में व्यक्त किए गए खतरे को सामाजिक और सांस्कृतिक आधार पर पूरी तरह पुष्ट और स्पष्ट करता है।

219. (C) निवारण के माध्यम से राष्ट्रीय अस्तित्व सुनिश्चित करना।
परमाणु हथियारों के अधिग्रहण को अक्सर 'रक्षात्मक' तर्क के साथ उचित ठहराया जाता है। राष्ट्रों का तर्क होता है कि एक अराजक और असुरक्षित विश्व में परमाणु शक्ति होना ही उनके अस्तित्व की एकमात्र गारंटी है, क्योंकि यह किसी भी संभावित हमलावर के मन में प्रतिशोध का ऐसा भय पैदा करता है कि वह आक्रमण करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। यह निवारण की नीति का आधार है। यहाँ परमाणु हथियार युद्ध लड़ने के लिए नहीं, बल्कि उसे होने से रोकने और अपनी संप्रभुता को अक्षुण्ण रखने के लिए एक 'बीमा' के रूप में देखे जाते हैं। यह यथार्थवादी सुरक्षा दृष्टिकोण का एक चरम स्वरूप है।

220. (A) पूंजीवाद और लोकतंत्र बनाम साम्यवादी व्यवस्था।
शीतयुद्ध केवल दो देशों के बीच की शक्ति की लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह दो विरोधी विचारधाराओं के बीच का एक वैश्विक संघर्ष था। एक ओर संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में उदारवादी लोकतंत्र और मुक्त बाजार पूंजीवाद का मॉडल था, तो दूसरी ओर सोवियत संघ के नेतृत्व में साम्यवाद और राज्य-नियंत्रित अर्थव्यवस्था थी। ये विचारधाराएं जीवन के हर पहलू—राजनीति, समाज और संस्कृति—के प्रति पूरी तरह अलग दृष्टिकोण रखती थीं। विचारधारा की इस गहराई ने ही विश्व को दो कट्टर गुटों में विभाजित कर दिया, जहाँ प्रत्येक पक्ष अपनी व्यवस्था को सार्वभौमिक रूप से श्रेष्ठ और अनिवार्य मानता था।

221. (D) संचार
संचार दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में इस बात पर सर्वाधिक ध्यान देता है कि संदेशों का आदान-प्रदान और उनकी व्याख्या कैसे की जाती है। इस दृष्टिकोण के अनुसार, कोई भी स्थिति तब तक 'संकट' नहीं बनती जब तक कि नीति निर्माता और मीडिया उसे उस रूप में चित्रित और प्रचारित न करें। भाषा, प्रतीकों और सूचनाओं का उपयोग धारणा बनाने में निर्णायक होता है। यह सिद्धांत यह विश्लेषण करता है कि कैसे शब्दों का चुनाव और सूचनाओं का नियंत्रण संघर्ष को बढ़ा सकता है या शांति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। अतः संचार की प्रक्रिया ही अंतर्राष्ट्रीय वास्तविकता को गढ़ने और उसे प्रबंधित करने का मुख्य आधार है।

222. (B) अस्तित्व और आत्म-संरक्षण
अंतर्राष्ट्रीय कानून में प्रत्येक राज्य का सबसे बुनियादी और सर्वोपरि अधिकार अपने 'अस्तित्व' को बनाए रखना और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यह अधिकार संप्रभुता के विचार से सीधे जुड़ा है, क्योंकि यदि राज्य का अस्तित्व ही नहीं रहेगा, तो उसके अन्य सभी अधिकारों का कोई मूल्य नहीं रह जाएगा। इसी अधिकार के कारण राज्यों को आत्मरक्षा के लिए बल प्रयोग करने की सीमित अनुमति प्राप्त है। यह अधिकार ही वह आधार है जिस पर राष्ट्र अपनी पूरी सुरक्षा रणनीति और विदेश नीति का निर्माण करते हैं। यह अराजक अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में जीवित रहने की प्रत्येक राज्य की कानूनी और स्वाभाविक प्राथमिकता है।

223. (C) वैश्वीकरण
वैश्वीकरण को अक्सर राष्ट्रों के बीच की बढ़ती हुई 'परस्पर संबद्धता' और 'एकीकरण' के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यापार, निवेश, तकनीकी नवाचार और मानवीय अंतःक्रियाएं राष्ट्रीय सीमाओं को पार कर वैश्विक स्तर पर एक विशाल नेटवर्क बनाती हैं। इसमें न केवल सरकारें, बल्कि निजी कंपनियां और आम नागरिक भी

Click Here to Buy book on Amazon

माध्यम से आने वाली पीढ़ियों और पर्यावरण को भी नष्ट कर देते हैं। परमाणु युद्ध में कोई वास्तविक विजेता नहीं हो सकता, क्योंकि इसका परिणाम मानवता का पूर्ण विनाश होने की संभावना रखता है।

191. (C) शांतिपूर्ण साधन
संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार, सभी राज्यों का यह कानूनी कर्तव्य है कि वे अपने अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाएं ताकि विश्व शांति और सुरक्षा खतरे में न पड़े। इसमें वार्ता, जांच, मध्यस्थता, सुलह, अधिनिर्णय और न्यायिक समाधान जैसे विभिन्न कूटनीतिक और विधिक विकल्प शामिल हैं। बल प्रयोग या युद्ध को अंतिम और केवल आत्मरक्षा की स्थिति तक ही सीमित रखा गया है। यह विधिक ढांचा अराजकता को रोकने और यह सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है कि राष्ट्रों के बीच के मतभेद रक्तपात के बजाय तर्क और कानून के माध्यम से सुलझाए जा सकें।

192. (D) उच्च हताहतों और आर्थिक लागत की संभावना।
सैन्य शक्ति का प्रयोग कभी भी जोखिम मुक्त नहीं होता और यह कई व्यावहारिक सीमाओं से बंधा होता है। किसी भी युद्ध या सैन्य अभियान में अपने सैनिकों की जान जाने का डर और युद्ध के संचालन में होने वाला भारी आर्थिक खर्च राज्य के लिए एक बड़ी बाधा है। यदि युद्ध लंबा खिंचता है, तो यह देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर सकता है और घरेलू स्तर पर सामाजिक अस्थिरता पैदा कर सकता है। इसके अतिरिक्त, आधुनिक युग में जनहानि के प्रति बढ़ती संवेदनशीलता नेताओं को बल प्रयोग करने से पहले कई बार सोचने पर मजबूर करती है। अतः लागत-लाभ का विश्लेषण शक्ति की सबसे बड़ी सीमा है।

193. (A) वैश्वीकरण
वैश्वीकरण का मूल मंत्र 'वैश्विक परस्पर संबद्धता' है, जहाँ भौगोलिक दूरियां अब बाधा नहीं रही हैं। सूचना प्रौद्योगिकी, इंटरनेट और एकीकृत बाजारों के कारण दुनिया के एक कोने में होने वाली कोई भी महत्वपूर्ण घटना बिजली की गति से पूरी दुनिया को प्रभावित करती है। यह परस्पर निर्भरता राज्यों को एक साझा वैश्विक समाज का हिस्सा बनाती है, जहाँ राष्ट्रीय सीमाएं पारगम्य हो गई हैं। वैश्वीकरण ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आधुनिक युग में कोई भी राष्ट्र बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटकर सुरक्षित या समृद्ध नहीं रह सकता है।

194. (A) P-3, Q-4, R-1, S-2
यथार्थवाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को शक्ति और सुरक्षा के निरंतर संघर्ष के रूप में देखता है जहाँ राज्य प्रमुख अभिनेता हैं। आदर्शवाद नैतिकता, कानून और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के माध्यम से शांति की वकालत करता है। निर्णय-प्रक्रिया दृष्टिकोण विदेश नीति के निर्माण में नौकरशाही और मानवीय कारकों की सूक्ष्म जांच करता है। व्यवस्था सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की समग्र संरचना और शक्ति के वितरण पर ध्यान केंद्रित करता है। ये चारों सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने के लिए अलग-अलग लेकिन पूरक दृष्टिकोण प्रदान करते हैं, जो क्रमशः शक्ति, मूल्य, प्रक्रिया और संरचनात्मक कारकों पर आधारित विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं।

195. (C) शस्त्र नियंत्रण
शस्त्र नियंत्रण का तात्पर्य उन समझौतों से है जो हथियारों की संख्या, उनके प्रकार या उनकी तैनाती को विनियमित और सीमित करने के लिए किए जाते हैं। बैलिस्टिक मिसाइलों की संख्या तय करना इसी का एक हिस्सा है, क्योंकि यह हथियारों की होड़ को नियंत्रित कर युद्ध के जोखिम को कम करने का प्रयास करता है। यह पूर्ण निरस्त्रीकरण नहीं है, क्योंकि इसमें हथियारों को पूरी तरह समाप्त नहीं किया जाता, बल्कि उन्हें एक प्रबंधनीय सीमा के भीतर रखा जाता है। ऐसे समझौते राष्ट्रों के बीच विश्वास बढ़ाने और रणनीतिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए कूटनीति के अत्यंत महत्वपूर्ण विधिक उपकरण माने जाते हैं।

196. (B) यथार्थवादी, जो युद्ध को राज्य के एक उपकरण के रूप में देखता है।
यथार्थवादी दृष्टिकोण यह मानता है कि युद्ध कोई आकस्मिक घटना नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रों द्वारा अपने विशिष्ट राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपनाया गया एक सोचे-समझे साधन का हिस्सा है। जब कूटनीति और वार्ता विफल हो जाती है, तो राज्य अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा या विस्तार के लिए सैन्य बल का सहारा लेते हैं। यथार्थवादियों के अनुसार, युद्ध राजनीति का ही एक हिंसक और प्रत्यक्ष विस्तार है। यह विचार युद्ध को मानवीय विफलता के बजाय अंतर्राष्ट्रीय अराजकता में जीवित रहने और शक्ति प्रदर्शन की एक तार्किक एवं रणनीतिक आवश्यकता के रूप में प्रस्तुत करता है।

197. (D) अनुसमर्थन
अनुसमर्थन संधि प्रक्रिया का वह अनिवार्य चरण है जिसमें कोई राज्य औपचारिक रूप से यह घोषणा करता है कि वह उस संधि की शर्तों से कानूनी रूप से बंधने के लिए तैयार है। केवल हस्ताक्षर करना पर्याप्त नहीं होता, क्योंकि हस्ताक्षर अक्सर केवल सहमति का प्राथमिक संकेत होते हैं। अनुसमर्थन आमतौर पर देश के आंतरिक संवैधानिक नियमों के बाद होता है। एक बार जब राज्य अनुसमर्थन के दस्तावेज जमा कर देता है, तो वह संधि उस पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत पूर्णतः बाध्यकारी हो जाती है। यह राष्ट्र की स्वेच्छा और विधिक प्रतिबद्धता का अंतिम प्रमाण है।

198. (A) विचारधारा
विचारधारा राष्ट्रवाद को एक आक्रामक और विस्तारवादी दिशा दे सकती है, जिससे वह संघर्ष का कारण बन जाता है। जब कोई राष्ट्र यह मानने लगता है कि उसकी संस्कृति, नस्ल या राजनीतिक व्यवस्था श्रेष्ठ है और उसे अन्य क्षेत्रों पर शासन करने का प्राकृतिक अधिकार है, तो यह 'विचारधारा' युद्ध की ओर ले जाती है। यह वैचारिक उन्माद जनता को युद्ध के लिए एकजुट करने और विदेशी आक्रमण को न्यायसंगत सिद्ध करने का शक्तिशाली माध्यम बनता है। इतिहास में आक्रामक राष्ट्रवाद और वैचारिक कट्टरता के संगम ने कई विनाशकारी युद्धों को

NODIA

248. (A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
अंतर्राष्ट्रीय कानून में घरेलू कानून की तरह कोई अनिवार्य प्रवर्तन तंत्र या विश्व पुलिस नहीं है। इस कमी के बावजूद राज्य कानून का पालन करते हैं क्योंकि यह उनके दीर्घकालिक हित में है। कारण स्पष्ट करता है कि प्रवर्तन का मुख्य आधार 'पारस्परिकता' है—यदि एक राज्य नियम तोड़ता है, तो दूसरा भी ऐसा कर सकता है, जिससे दोनों का नुकसान होगा। इसके अतिरिक्त, आर्थिक प्रतिबंध और कूटनीतिक दबाव जैसे जवाबी उपाय राज्यों को विधिक मर्यादाओं में रहने के लिए मजबूर करते हैं। अतः कारण अभिकथन के पीछे के व्यावहारिक और संरचनात्मक तर्क को पूरी तरह स्पष्ट करता है।

249. (A) शक्ति का अधिग्रहण
शक्ति के अधिग्रहण में उन भौतिक और ठोस संसाधनों को बढ़ाना शामिल है जो किसी राष्ट्र की वैश्विक स्थिति को मजबूत करते हैं। एक विकसित सैन्य-औद्योगिक परिसर उन्नत हथियारों की आपूर्ति सुनिश्चित करता है, तकनीकी नवाचार राष्ट्र को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करता है, और मजबूत आर्थिक उत्पादन इन सभी गतिविधियों के लिए आवश्यक धन प्रदान करता है। ये सभी 'मूर्त तत्व' हैं क्योंकि इन्हें मापा और देखा जा सकता है। यह संचय ही राष्ट्र को अन्य राज्यों के व्यवहार को प्रभावित करने और एक प्रतिस्पर्धी अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में अपने राष्ट्रीय हितों को सफलतापूर्वक प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।

250. (C) पारंपरिक युद्ध
पारंपरिक युद्ध संघर्ष का वह स्वरूप है जिसमें राष्ट्रों की नियमित सेनाएं आमने-सामने होती हैं और वे टैंक, लड़ाकू विमान और जहाजों जैसे पारम्परिक हथियारों का उपयोग करती हैं। इसमें सामूहिक विनाश के हथियारों का प्रयोग नहीं किया जाता। यह युद्ध नियमों और स्थापित सैन्य रणनीतियों के तहत लड़ा जाता है। यद्यपि यह अत्यंत विनाशकारी हो सकता है, लेकिन इसका प्रभाव परमाणु युद्ध की तरह पूरी मानवता या आने वाली पीढ़ियों के लिए सर्वनाशकारी नहीं होता। इतिहास के अधिकांश युद्ध इसी श्रेणी में आते हैं, जहाँ विजय सैन्य कौशल और संसाधनों के कुशल प्रयोग पर निर्भर करती है।

251. (D) विचारधारा
'इतिहास का अंत' का प्रसिद्ध विचार फ्रांसिस फुकुयामा द्वारा शीतयुद्ध की समाप्ति पर प्रस्तुत किया गया था। यह दावा करता था कि मानव जाति का वैचारिक विकास अब अपने चरम पर पहुँच गया है और पश्चिमी उदारवादी लोकतंत्र ही शासन का अंतिम स्वरूप है। यह केवल एक राजनीतिक घटना नहीं थी, बल्कि साम्यवाद जैसी प्रतिस्पर्धी 'विचारधारा' की हार और लोकतंत्र की विजय की घोषणा थी। यह दर्शाता है कि विचारधाराएं राष्ट्रों के बीच संघर्ष को कैसे प्रेरित करती हैं और उनकी जीत या हार पूरी वैश्विक व्यवस्था की दिशा और सोच को कैसे बदल देती है।

252. (B) खेल सिद्धांत
'चिकन का खेल' खेल सिद्धांत का एक प्रसिद्ध मॉडल है जो अंतर्राष्ट्रीय संकटों, विशेष रूप से परमाणु गतिरोध, के दौरान राज्यों के व्यवहार को समझने के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें दो पक्ष एक-दूसरे के आमने-सामने होते और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं होता, क्योंकि पीछे हटने वाले को 'कायर' माना जाएगा। हालांकि, यदि दोनों में से कोई भी पीछे नहीं हटा, तो भयानक युद्ध होगा जिसमें दोनों नष्ट हो जाएंगे। यह मॉडल यह विश्लेषण करता है कि कैसे तर्कसंगत अभिनेता हारने की प्रतिष्ठा और सर्वनाश के खतरे के बीच अत्यंत कठिन और रणनीतिक निर्णय लेते हैं।

253. (C) अपनी सीमाओं का अधिकतम संभव सीमा तक विस्तार करना।
पारंपरिक अंतर्राष्ट्रीय कानून राज्यों को क्षेत्रीय अखंडता के अधिकार देता है, लेकिन वह क्षेत्र विस्तार को राज्य का कर्तव्य नहीं मानता। वास्तव में, आधुनिक कानून बल प्रयोग के माध्यम से अन्य राज्यों के क्षेत्रों पर कब्जा करने को एक गंभीर अपराध और अवैध कार्य मानता है। इसके विपरीत, संधियों का पालन करना, अन्य राज्यों की स्वतंत्रता का सम्मान करना और विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाया जाना राज्यों के अनिवार्य कानूनी और नैतिक कर्तव्य हैं। क्षेत्रीय विस्तार की इच्छा अक्सर युद्ध का कारण बनती है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय कानून पूरी तरह हतोत्साहित करने और विनियमित करने का प्रयास करता है।

254. (C) P-4, Q-3, R-2, S-1
यथार्थवाद युद्ध को शक्ति संतुलन और निवारण के माध्यम से रोकने की बात करता है। आदर्शवाद अंतर्राष्ट्रीय कानून और संस्थानों को शांति का आधार मानता है। संचार सिद्धांत के अनुसार, संकेतों को स्पष्ट करके और गलतफहमी दूर करके युद्ध टाले जा सकते हैं। खेल सिद्धांत लाभ संरचनाओं को बदलकर सहयोग को प्रोत्साहित करने का सुझाव देता है। ये चारों दृष्टिकोण युद्ध की रोकथाम के लिए अलग-अलग रणनीतियां प्रस्तुत करते हैं, जो क्रमशः शक्ति, नियम, सूचना और तर्कसंगत हितों पर आधारित हैं। ये सिद्धांत वैश्विक शांति बनाए रखने के लिए विभिन्न शैक्षणिक और व्यावहारिक मार्ग दिखाते हैं।

255. (A) आर्थिक वैश्वीकरण
आर्थिक वैश्वीकरण ने पूरी दुनिया को एक ही बाजार और उत्पादन केंद्र के रूप में संगठित कर दिया है। सीमा पार व्यापार में अभूतपूर्व वृद्धि और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के विकास का अर्थ है कि आज एक वस्तु के विभिन्न पुर्जे दुनिया के अलग-अलग देशों में बनते हैं। यह परस्पर निर्भरता राज्यों को आर्थिक रूप से एक-दूसरे से जोड़ती है, जिससे युद्ध की संभावना कम होती है क्योंकि संघर्ष सभी के लिए आर्थिक रूप से घाटे का सौदा होगा। यह प्रक्रिया राष्ट्रों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ाती है और वैश्विक स्तर पर समृद्धि के नए द्वार खोलती है, हालांकि इसके अपने आर्थिक जोखिम भी हैं।

256. (B) गुटनिरपेक्षता
जब कोई राज्य दो प्रतिस्पर्धी शक्तियों के संघर्ष में किसी का पक्ष न लेकर तटस्थ रहने और अपनी स्वतंत्र राह चुनने का निर्णय लेता है, तो वह गुटनिरपेक्षता का अभ्यास कर रहा होता है। यह नीति केवल निष्क्रियता नहीं है, बल्कि अपनी संप्रभुता

Downloaded from www.pdf.tube

होतीं, बल्कि वे उन लोगों की सोच से प्रभावित होती हैं जो सत्ता के शीर्ष पर बैठे हैं। यह विश्लेषण नेताओं के व्यक्तिगत विश्वासों, उनके अनुभवों और उनके मानसिक पूर्वाग्रहों की गहराई से जांच करता है ताकि यह समझा जा सके कि उन्होंने किसी विशेष परिस्थिति में युद्ध या शांति का चुनाव क्यों किया। यह दृष्टिकोण मानता है कि राज्य के भीतर निर्णय लेने की प्रक्रिया कोई यांत्रिक कार्य नहीं है, बल्कि यह मानवीय मनोवैज्ञानिक और संगठनात्मक जटिलताओं का एक जीवंत परिणाम है, जो इतिहास की दिशा बदल देता है।

208. (B) शीतयुद्ध की द्विध्रुवीय संरचना।
गुटनिरपेक्षता की नीति का उदय शीतयुद्ध के उस कठिन दौर में हुआ जब दुनिया संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के दो प्रतिस्पर्धी सैन्य गुटों में विभाजित थी। एशिया और अफ्रीका के नव-स्वतंत्र राष्ट्रों ने महसूस किया कि किसी भी एक पक्ष के साथ जुड़ना उनकी कठिनता से मिली आजादी और संप्रभुता के लिए खतरा हो सकता है। इसलिए, उन्होंने इन दोनों ध्रुवों से समान दूरी बनाए रखने और अपनी स्वतंत्र विदेश नीति चलाने का मार्ग चुना। यह नीति महाशक्तियों की वैचारिक प्रतिद्वंद्विता के बीच अपनी पहचान और शांति बनाए रखने के लिए इन राष्ट्रों की एक सशक्त और रणनीतिक प्रतिक्रिया थी।

209. (C) निवारण
निवारण का सिद्धांत इस मनोवैज्ञानिक धारणा पर कार्य करता है कि हमलावर को हमले से केवल तभी रोका जा सकता है जब उसे यह विश्वास हो जाए कि उसकी कार्रवाई के परिणामस्वरूप उसे विनाशकारी प्रतिशोध झेलना पड़ेगा। एक विशाल परमाणु शस्त्रागार बनाए रखना वास्तव में इसी 'भय की शांति' को स्थापित करने का एक तरीका है। यह नीति युद्ध लड़ने के लिए नहीं, बल्कि शत्रु को यह समझाने के लिए है कि युद्ध की कीमत किसी भी संभावित लाभ से कहीं अधिक होगी। यह अविश्वास पर आधारित एक रणनीतिक स्थिरता है जिसने परमाणु युग में महाशक्तियों के बीच सीधे टकराव को टालने में मदद की है।

210. (A) 2, 1, 4, 3
अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का शैक्षणिक विकास एक क्रमिक प्रक्रिया रही है। प्रथम विश्व युद्ध की विभीषिका के बाद आदर्शवाद उभरा, जिसने शांति और कानून पर जोर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जब आदर्शवाद विफल लगा, तब यथार्थवाद प्रमुख हुआ जिसने शक्ति की राजनीति को केंद्र में रखा। शीतयुद्ध के दौरान, इन दो महाशक्तियों के बीच गुटनिरपेक्षता की अवधारणा उन राष्ट्रों के लिए उभरी जो स्वतंत्र रहना चाहते थे। अंततः, 20वीं सदी के अंत में वैश्वीकरण और गैर-राज्य अभिनेताओं के उदय ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन को एक नया, बहुआयामी और परस्पर जुड़ा हुआ स्वरूप प्रदान किया है।

211. (C) अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था अराजक है।
यथार्थवादी विचारधारा की सबसे मौलिक और केंद्रीय धारणा 'अराजकता' है। इसका अर्थ यह नहीं है कि विश्व में अव्यवस्था है, बल्कि इसका तात्पर्य यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्यों के ऊपर शासन करने वाली और कानून लागू करने वाली कोई सर्वोच्च विधिक सत्ता या विश्व सरकार नहीं है। इस अराजक स्थिति के कारण प्रत्येक संप्रभु राज्य अपनी सुरक्षा के लिए स्वयं उत्तरदायी होता है, जिससे उनमें असुरक्षा और शक्ति संचय की निरंतर प्रतिस्पर्धा बनी रहती है। यही अराजकता राज्यों को स्वार्थी होने और अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने के लिए विवश करती है, जो यथार्थवाद के अनुसार वैश्विक राजनीति का कड़वा सच है।

212. (A) वैश्वीकरण
आर्थिक वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसने राष्ट्रीय सीमाओं के महत्व को कम करते हुए पूरी दुनिया को एक एकीकृत बाजार में बदल दिया है। व्यापार के उदारीकरण, सीमा पार निवेश में वृद्धि और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के विस्तार के कारण आज विभिन्न राष्ट्रों की अर्थव्यवस्थाएं एक-दूसरे के साथ गहराई से जुड़ गई हैं। इस परस्पर निर्भरता का अर्थ है कि एक देश में होने वाली आर्थिक हलचल का प्रभाव वैश्विक स्तर पर महसूस किया जाता है। वैश्वीकरण ने न केवल वस्तुओं और सेवाओं का, बल्कि विचारों और तकनीक का भी तीव्र प्रवाह सुनिश्चित किया है, जिससे राष्ट्रों के बीच सहयोग के नए अवसर और चुनौतियाँ दोनों उत्पन्न हुई हैं।

213. (D) विवादों का शांतिपूर्ण समाधान
अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कूटनीति का मुख्य कार्य विवादों को बिना हिंसा के सुलझाना है। जब दो राष्ट्र वार्ता के माध्यम से किसी सामान्य सहमति पर नहीं पहुँच पाते और अंततः युद्ध का सहारा लेते हैं, तो यह सीधे तौर पर 'विवादों के शांतिपूर्ण समाधान' की विफलता को दर्शाता है। इसका अर्थ है कि संचार के रास्ते बंद हो गए हैं और मध्यस्थता या कानूनी विधियां तनाव कम करने में असमर्थ रही हैं। बल प्रयोग कूटनीति का अंत है और यह अराजकता की ओर एक कदम है। शांतिपूर्ण समाधान की विफलता अक्सर सुरक्षा दुविधा और अविश्वास के कारण होती है, जहाँ राष्ट्रों को सैन्य शक्ति ही एकमात्र विकल्प नजर आती है।

214. (B) स्वयं राज्य से ऊपर किसी उच्च सत्ता की अनुपस्थिति।
अंतर्राष्ट्रीय कानून में संप्रभुता का अर्थ है कि राज्य अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर पूर्णतः स्वतंत्र है और कानूनी रूप से किसी बाहरी शक्ति के आदेश मानने के लिए बाध्य नहीं है। यह अवधारणा इस विचार पर आधारित है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में सभी राज्य समान रूप से स्वतंत्र हैं और उनके ऊपर कोई ऐसी 'सुपर-स्टेट' या विश्व सरकार नहीं है जो उनकी मर्जी के खिलाफ उन पर कानून थोप सके। यद्यपि राज्य संधियों और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करते हैं, वे ऐसा अपनी सहमति और संप्रभु इच्छा से करते हैं। यह स्वतंत्रता ही राज्य के व्यक्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण विधिक लक्षण मानी जाती है।

215. (C) वैचारिक/धार्मिक
जब किसी युद्ध का मूल कारण 'पवित्र भूमि' पर दावे या किसी विशिष्ट धार्मिक दर्शन को श्रेष्ठ सिद्ध करने का जुनून होता है, तो वह वैचारिक या धार्मिक युद्ध की श्रेणी में आता है। ऐसे संघर्ष अक्सर पहचान और विश्वास की गहरी भावनाओं से जुड़े होते हैं, जो उन्हें अत्यधिक हिंसक और समझौताहीन बना देते हैं। यहाँ

NODIA

का आधार मानता है। उनका मानना है कि संस्थागत विकास मानवीय तर्क को राजनीति में ऊपर रखने का एकमात्र प्रभावी तरीका है।

232. (B) जैव-रासायनिक युद्ध
जैव-रासायनिक युद्ध संघर्ष का वह अमानवीय स्वरूप है जिसमें पारम्परिक शस्त्रों के बजाय सूक्ष्मजीवों या घातक जहरीले रसायनों का उपयोग किया जाता है। इन्हें 'चुपके से मारने वाले हथियार' भी कहा जाता है क्योंकि इनका प्रभाव तुरंत नहीं बल्कि धीरे-धीरे और व्यापक रूप से फैलता है। ये हथियार निर्दोष नागरिकों और पर्यावरण को भी नष्ट कर देते हैं, जिससे इनका उपयोग करना अत्यंत अनैतिक माना जाता है। इनकी विनाशकता के कारण अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने विभिन्न संधियों के माध्यम से इनके निर्माण और युद्ध में उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है, हालांकि इनके प्रसार का खतरा आज भी बना हुआ है।

233. (C) संधि कानून
'पाक्टा संट सरवेंडा' का सिद्धांत संधि कानून की वह आत्मा है जो यह सुनिश्चित करती है कि अंतर्राष्ट्रीय समझौते केवल कागज के टुकड़े बनकर न रह जाएं। यह सिद्धांत राज्यों को नैतिक और कानूनी रूप से बाध्य करता है कि वे अपने द्वारा हस्ताक्षरित संधियों का पालन पूरी ईमानदारी और सद्भावना के साथ करें। यह अराजक अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में राज्यों के बीच विश्वास और सहयोग की नींव रखता है। यदि राष्ट्रों के बीच समझौतों का सम्मान करने की परंपरा न हो, तो कूटनीति का पूरा ढांचा ही गिर जाएगा। अतः संधि कानून ही वह विधिक तंत्र है जो वैश्विक संबंधों में स्थिरता और पूर्वानुमान सुनिश्चित करता है।

234. (D) कथन I असत्य है, लेकिन कथन II सत्य है।
शीतयुद्ध के समापन ने महाशक्तियों के बीच परमाणु युद्ध के महान भय को तो समाप्त कर दिया, लेकिन इसका अर्थ शांति का आगमन नहीं था। कथन II बिल्कुल सही है क्योंकि 1991 के बाद दुनिया ने नए और अधिक जटिल सुरक्षा खतरों का सामना किया है। इनमें आंतरिक गृहयुद्ध, भीषण जातीय और धार्मिक संघर्ष, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, साइबर युद्ध और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दे प्रमुख हैं। आधुनिक संघर्ष अब केवल सीमाओं पर नहीं लड़े जाते, बल्कि वे राष्ट्रों के भीतर और वैश्विक नेटवर्क के रूप में उभरे हैं। अतः शीतयुद्ध के बाद की दुनिया और भी अधिक अनिश्चित चुनौतियों से भरी हुई है।

235. (C) यथार्थवाद
यथार्थवादी विचारधारा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक 'शून्य-योग खेल' के रूप में देखती है जहाँ प्रत्येक राज्य अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है। यह मानता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था अराजक है और यहाँ किसी अन्य राज्य पर पूर्ण भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। इसलिए, एक यथार्थवादी राज्य अपनी सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है और निरंतर शक्ति बढ़ाने का प्रयास करता है ताकि वह किसी भी संभावित हमले से बच सके। इस दृष्टिकोण में स्वार्थ और शक्ति ही राष्ट्रों के व्यवहार के मुख्य चालक हैं। यहाँ नैतिकता के स्थान पर व्यावहारिक हितों और सैन्य मजबूती को ही सफलता का वास्तविक मापदंड माना जाता है।

236. (A) कूटनीति
कूटनीति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को संचालित करने का वह शांतिपूर्ण माध्यम है जिसमें अनुनय, तर्कपूर्ण वार्ता और परस्पर समझौते की कला का उपयोग किया जाता है। इसका लक्ष्य बल प्रयोग के बिना राष्ट्रों के बीच के मतभेदों को सुलझाना और सामान्य हितों को बढ़ावा देना है। कूटनीतिज्ञ अपने देश के हितों का प्रतिनिधित्व करते हुए शत्रुता को सहयोग में बदलने और अविश्वास को दूर करने का निरंतर प्रयास करते हैं। यह अराजक विश्व में व्यवस्था बनाए रखने का सबसे परिष्कृत उपकरण है, जो युद्ध की विभीषिका के विरुद्ध एक ढाल के रूप में कार्य करता है और राष्ट्रों को शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व का मार्ग दिखाता है।

237. (D) अंतर्राष्ट्रीय कानून।
अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक आधारभूत नियम यह है कि प्रत्येक राज्य को दूसरे राज्य की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का पूर्ण सम्मान करना चाहिए। यह नियम संयुक्त राष्ट्र चार्टर का भी मूल आधार है, जो किसी भी राष्ट्र की सीमाओं के विरुद्ध बल प्रयोग या हस्तक्षेप को अवैध मानता है। क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना ही वह मौलिक कर्तव्य है जो राष्ट्रों को शांतिपूर्वक अपनी सीमाओं के भीतर रहने और विकास करने की गारंटी देता है। इसके बिना, विश्व राजनीति केवल शक्तिशाली राज्यों द्वारा निर्बल राज्यों के क्षेत्रों पर कब्जा करने की एक निरंतर चलने वाली हिंसक होड़ बन जाएगी, जिससे वैश्विक अशांति फैलेगी।

238. (B) निर्णय-प्रक्रिया दृष्टिकोण
निर्णय-प्रक्रिया दृष्टिकोण इस यथार्थवादी भ्रम को तोड़ता है कि राज्य सदैव पूरी तरह तर्कसंगत और एकजुट होकर कार्य करता है। यह स्पष्ट करता है कि विदेश नीति अक्सर सरकार के भीतर मौजूद विभिन्न नौकरशाही संगठनों—जैसे विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और गुप्तचर विभाग—के बीच होने वाली सौदेबाजी और खींचतान का परिणाम होती है। प्रत्येक विभाग अपने नजरिए और हितों को प्राथमिकता देता है, जिससे अंतिम नीति अक्सर एक 'समझौते' के रूप में उभरती है। यह विश्लेषण राज्य के भीतर की जटिल निर्णय लेने वाली मशीनरी को उजागर करता है, जो दर्शाती है कि नीतियां केवल बाहरी खतरों से नहीं, बल्कि आंतरिक राजनीति से भी प्रभावित होती हैं।

239. (C) यथार्थवाद
यथार्थवाद के केंद्र में 'शक्ति' की अवधारणा है। यह सिद्धांत अध्ययन करता है कि राज्य अपनी सुरक्षा के लिए शक्ति कैसे प्राप्त करते हैं, वे अपने हितों को साधने के लिए इस शक्ति का उपयोग कैसे करते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में शक्ति संतुलन या अन्य बाधाएं उनके प्रभाव को कैसे सीमित करती हैं। यथार्थवादियों के अनुसार, शक्ति ही वह भाषा है जिसे अराजक विश्व में सभी राज्य समझते हैं। शक्ति का यह त्रिकोणीय विश्लेषण—अधिग्रहण, उपयोग और सीमाएं—यथार्थवाद को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की कठोर वास्तविकताओं को समझने के

Click Here to Buy book on Amazon

सक्रिय भागीदार होते हैं। वैश्वीकरण ने दुनिया को आर्थिक और सामाजिक रूप से इतना अधिक जोड़ दिया है कि कोई भी देश अब पूरी तरह स्वायत्त रहकर प्रगति नहीं कर सकता। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसने आधुनिक जीवन के प्रत्येक आयाम को वैश्विक रंग में रंग दिया है।

224. (B) P-3, Q-4, R-1, S-2
शस्त्रों की दौड़ का विपरीत 'निरस्त्रीकरण' है क्योंकि एक हथियारों को बढ़ाता है और दूसरा उन्हें घटाता है। हस्तक्षेप का विपरीत 'संप्रभुता' का सम्मान है, क्योंकि संप्रभुता गैर-हस्तक्षेप की मांग करती है। गठबंधन का विपरीत 'गुटनिरपेक्षता' है, जहाँ एक सैन्य गुटों में जुड़ने पर आधारित है और दूसरा उनसे स्वतंत्र रहने पर। युद्ध का विपरीत 'शांतिपूर्ण समाधान' है, क्योंकि एक बल प्रयोग का रास्ता है और दूसरा वार्ता का। ये सुमेलित शब्द अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मूलभूत विरोधाभासों और उनके समाधान के विभिन्न विकल्पों को स्पष्ट रूप से समझने में सहायता करते हैं, जो क्रमशः शक्ति संघर्ष और शांति स्थापना के मार्ग हैं।

225. (A) राज्य के पास प्रतिशोध की क्षमता और उसका उपयोग करने की बोधित इच्छा दोनों हो।
निवारण केवल हथियारों के होने से सफल नहीं होता, बल्कि इसकी प्रभावशीलता दो मुख्य स्तंभों पर टिकी है—क्षमता और विश्वसनीयता। शत्रु को यह विश्वास होना चाहिए कि आपके पास उसे नष्ट करने के लिए पर्याप्त हथियार हैं और यह भी कि आक्रमण की स्थिति में आप उन हथियारों का उपयोग करने का साहस और संकल्प रखते हैं। यदि शत्रु को लगता है कि आप केवल खाली धमकी दे रहे हैं या आपका नेतृत्व कमजोर है, तो निवारण विफल हो जाएगा। अतः निवारण एक मनोवैज्ञानिक खेल है जहाँ शत्रु के मानस में अपने प्रतिशोध की 'निश्चितता' बैठाना ही सफलता की कुंजी है।

226. (B) शांति को बढ़ावा देने वाले तर्कसंगत संस्थानों और कानूनों द्वारा इसे दूर किया जा सकता है।
आदर्शवादी दृष्टिकोण यह मानता है कि विचारधाराएं अक्सर अविश्वास और संघर्ष का कारण बनती हैं, लेकिन वे स्थायी बाधाएं नहीं हैं। आदर्शवादियों के अनुसार, यदि राष्ट्र तर्कसंगत संवाद करें और मजबूत अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों एवं नियमों के तहत कार्य करें, तो वे अपने वैचारिक मतभेदों को पीछे छोड़कर साझा मानवीय हितों के लिए सहयोग कर सकते हैं। वे मानते हैं कि शिक्षा, लोकतंत्र और कानून के माध्यम से संकीर्ण विचारधाराओं के प्रभाव को कम किया जा सकता है। यह दृष्टिकोण एक ऐसे भविष्य की कल्पना करता है जहाँ वैश्विक सहयोग और कानून की सर्वोच्चता किसी भी विभाजनकारी विचारधारा पर भारी पड़ेगी।

227. (D) सार्वजनिक बहस, विशेषज्ञ राय और राजनीतिक नेतृत्व की एक प्रक्रिया।
राष्ट्रीय हित का निर्धारण कोई बंद कमरे की प्रक्रिया नहीं है। इसमें संसद, मीडिया, थिंक टैंक और नागरिक समाज के बीच होने वाली व्यापक बहस शामिल होती है। विभिन्न राजनीतिक दल अपने-अपने दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं और विशेषज्ञ अपनी राय देते हैं। अंततः, निर्वाचित नेतृत्व इन सभी इनपुट और बाहरी अंतर्राष्ट्रीय वास्तविकताओं को ध्यान में रखकर निर्णय लेता है। यह प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि देश की विदेश नीति केवल कुछ व्यक्तियों की पसंद न होकर राष्ट्र की व्यापक सहमति और उसकी बुनियादी जरूरतों को प्रतिबिंबित करे।

228. (B) गठबंधनों
शीतयुद्ध काल की सबसे प्रमुख संरचनात्मक विशेषता दुनिया का दो शक्तिशाली सैन्य गठबंधनों में विभाजित होना था। संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में नाटो और सोवियत संघ के नेतृत्व में वारसॉ पैक्ट ने सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांतों के आधार पर अपने-अपने प्रभाव क्षेत्रों को संगठित किया। ये गठबंधन अविश्वास और सुरक्षा दुविधा का सीधा परिणाम थे, जहाँ प्रत्येक पक्ष ने अपनी शक्ति बढ़ाने और दूसरे को संतुलित करने के लिए मित्र राष्ट्रों का एक मजबूत नेटवर्क तैयार किया। इन गठबंधनों ने ही शीतयुद्ध के दौरान वैश्विक राजनीति को एक स्थिर लेकिन तनावपूर्ण द्विध्रुवीय ढांचा प्रदान किया, जिसने शांति और संघर्ष को नियंत्रित किया।

229. (C) विदेश नीति के निर्णय कौन और कैसे लेता है?
निर्णय-प्रक्रिया दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के वास्तविक कार्यप्रणाली को समझना है। यह उन बुनियादी सवालों पर ध्यान केंद्रित करता है कि निर्णय लेने वाले व्यक्ति कौन हैं, उनकी मनोवैज्ञानिक स्थिति क्या है, और सरकारी विभागों के बीच सूचनाओं का आदान-प्रदान कैसे होता है। यह केवल इस बात से संतुष्ट नहीं होता कि राज्य ने क्या किया, बल्कि यह जानना चाहता है कि वह निर्णय किन परिस्थितियों और आंतरिक प्रक्रियाओं के माध्यम से लिया गया। यह विश्लेषण राज्य के व्यवहार को अधिक मानवीय और सूक्ष्म स्तर पर समझने की कोशिश करता है, जो इसे अन्य सिद्धांतों से अलग बनाता है।

230. (D) 1, 2 और 3
किसी भी राष्ट्र की कुल शक्ति इन तीनों तत्वों के संतुलित योग से बनती है। सैन्य और आर्थिक क्षमता शक्ति का ठोस आधार प्रदान करती हैं। नेतृत्व की कुशलता और जनता का उत्साह जैसे अमूर्त तत्व इन संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करते हैं। इसके अतिरिक्त, किसी देश की राजनीतिक विचारधारा और उसकी शासन व्यवस्था का आकर्षण उसे दुनिया भर में मित्र बनाने और बिना बल प्रयोग के प्रभाव बढ़ाने में मदद करता है। अतः शक्ति का एक पूर्ण विश्लेषण इन सभी भौतिक, मनोवैज्ञानिक और वैचारिक पहलुओं को समाहित करने की मांग करता है, जो मिलकर राष्ट्र की वैश्विक स्थिति तय करते हैं।

231. (D) अंतर्राष्ट्रीय कानून और संस्थानों का विकास
आदर्शवादी परंपरा का यह दृढ़ विश्वास है कि अराजक विश्व को नियम-आधारित व्यवस्था में बदलकर युद्धों को स्थायी रूप से रोका जा सकता है। उनका तर्क है कि जब राष्ट्र साझा कानूनों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के माध्यम से एक-दूसरे के प्रति जवाबदेह होते हैं, तो संघर्ष की संभावना कम हो जाती है। ये संस्थान विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए मंच प्रदान करते हैं और सामूहिक सुरक्षा की गारंटी देते हैं। आदर्शवाद शक्ति के स्थान पर विधिक विमर्श और नैतिक प्रतिबद्धता को शांति

Downloaded from www.pdf.tube

के अनुसार, शीतयुद्ध की समाप्ति कोई वैचारिक या नैतिक विजय नहीं थी, बल्कि यह सोवियत संघ की आर्थिक और सैन्य कमजोरी का परिणाम थी जिससे वह महाशक्ति के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखने में असमर्थ हो गया। इस पतन ने उस द्विध्रुवीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया जिसने दशकों तक स्थिरता बनाए रखी थी। यह विश्लेषण व्यक्तिगत भावनाओं के बजाय इस बात पर जोर देता है कि कैसे एक ध्रुव के कमजोर होने से पूरी वैश्विक संरचना और शक्ति का समीकरण बदल गया।

183. (C) अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रबंधित करना और हिंसा का सहारा लिए बिना संघर्षों को हल करना।
कूटनीति का मूल उद्देश्य राष्ट्रों के बीच शांतिपूर्ण संवाद और वार्ता की प्रक्रिया को बनाए रखना है। यह वह कला है जिसके माध्यम से राज्य अपने राष्ट्रीय हितों को बिना युद्ध के प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। कूटनीतिज्ञों का कार्य मतभेदों को कम करना, गलतफहमियों को दूर करना और सहयोग के क्षेत्रों की तलाश करना है। एक सफल कूटनीति संघर्षों को रक्तपात में बदलने से पहले ही हल कर लेती है। यह अराजक अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में स्थिरता और पूर्वानुमान लाने का सबसे महत्वपूर्ण मानवीय उपकरण है, जो सैन्य शक्ति के स्थान पर तर्कसंगत वार्ता को प्राथमिकता देता है।

184. (D) संप्रभु समानता
संप्रभु समानता का सिद्धांत यह मानता है कि प्रत्येक राज्य अपने क्षेत्र के भीतर सर्वोच्च है और कानून की दृष्टि में सभी राज्य बराबर हैं। इस समानता का अनिवार्य परिणाम यह है कि किसी भी राज्य को दूसरे के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। हस्तक्षेप न करना ही संप्रभुता का वास्तविक सम्मान है। यह सिद्धांत छोटे और निर्बल राष्ट्रों को शक्तिशाली राष्ट्रों के प्रभुत्व से सुरक्षा प्रदान करता है और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में न्यायपूर्ण सह-अस्तित्व की नींव रखता है। इसके बिना, विश्व राजनीति केवल शक्तिशाली राज्यों की मनमानी का अखाड़ा बनकर रह जाएगी।

185. (A) अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विचारधारा की भूमिका और प्रासंगिकता।
जब कोई राज्य अपनी विदेश नीति को केवल सुरक्षा तक सीमित न रखकर अपनी राजनीतिक विचारधारा के वैश्विक प्रसार को एक मिशन बना लेता है, तो यह विचारधारा की शक्ति को दर्शाता है। ऐसी नीतियां अक्सर उन मूल्यों से प्रेरित होती हैं जिन्हें वह राष्ट्र सार्वभौमिक मानता है। विचारधारा यहाँ राष्ट्रीय हित को परिभाषित करने और उसे एक नैतिक उद्देश्य प्रदान करने का कार्य करती है। यह राज्यों को अपने जैसे विचार वाले समूहों का समर्थन करने और विरोधियों को चुनौती देने के लिए प्रेरित करती है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वैचारिक ध्रुवीकरण और प्रतिस्पर्धा बढ़ती है।

186. (C) आदर्शवाद
आदर्शवादी दृष्टिकोण संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को वैश्विक शांति और सहयोग के लिए अनिवार्य उपकरणों के रूप में देखता है। आदर्शवादियों का मानना है कि सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था और एक साझा कानूनी मंच के माध्यम से अराजक विश्व को व्यवस्थित किया जा सकता है। उनके अनुसार, संयुक्त राष्ट्र केवल राज्यों की बातचीत का स्थान नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रों के व्यवहार को नियंत्रित करने और उन्हें नैतिक तथा कानूनी रूप से उत्तरदायी बनाने की क्षमता रखता है। यह विचारधारा शक्ति की राजनीति के विकल्प के रूप में वैश्विक संस्थागत सुधारों और नियम-आधारित सहयोग की वकालत करती है।

187. (A) शस्त्रों की दौड़
शस्त्रों की दौड़ प्रतिद्वंद्वी राज्यों के बीच सैन्य क्षमता बढ़ाने की एक निरंतर और प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया है। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब एक देश द्वारा अपनी सुरक्षा के लिए हथियार जुटाने को दूसरा देश एक संभावित खतरे के रूप में देखता है और प्रतिक्रियास्वरूप वह भी अपनी सेना को और अधिक आधुनिक और शक्तिशाली बनाने लगता है। यह प्रतिस्पर्धा अक्सर अविश्वास और भय के कारण स्वतः ही बढ़ती रहती है, जिससे युद्ध की संभावना और आर्थिक बोझ दोनों बढ़ जाते हैं। यह सुरक्षा दुविधा का एक ज्वलंत उदाहरण है जहाँ प्रत्येक पक्ष श्रेष्ठता प्राप्त करने की अंतहीन होड़ में लगा रहता है।

188. (A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
शीतयुद्ध के दौरान, एशिया और अफ्रीका के नव-स्वतंत्र राष्ट्रों ने महसूस किया कि अमेरिका या सोवियत संघ के नेतृत्व वाले किसी भी सैन्य गुट में शामिल होना उनकी संप्रभुता के लिए खतरा हो सकता है। वे अपने संसाधनों का उपयोग विकास के लिए करना चाहते थे, न कि दूसरों के युद्धों में। गुटनिरपेक्षता ने उन्हें इन वैचारिक और सैन्य टकरावों से दूर रहने और अपनी स्वतंत्र पहचान बनाए रखने का एक सशक्त मंच प्रदान किया। कारण बिल्कुल सही है क्योंकि महाशक्ति प्रतिद्वंद्विता से बचना ही इस नीति का प्राथमिक उद्देश्य था। अतः अभिकथन और कारण के बीच सीधा और तार्किक संबंध है।

189. (D) शक्ति
अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आर्थिक साधन, जैसे वित्तीय सहायता देना या व्यापारिक प्रतिबंध लगाना, राज्य की शक्ति के महत्वपूर्ण आयाम हैं। शक्ति केवल सैन्य बल नहीं है, बल्कि यह दूसरों को प्रभावित करने और उनके व्यवहार को अपने अनुकूल बदलने की समग्र क्षमता है। आर्थिक शक्ति का उपयोग अक्सर 'गाजर और छड़ी' की नीति के रूप में किया जाता है, जहाँ सहयोग के लिए पुरस्कार और विरोध के लिए दंड दिया जाता है। यह दर्शाता है कि कैसे कोई राष्ट्र अपनी आर्थिक मजबूती को कूटनीतिक प्रभाव और रणनीतिक लाभ में परिवर्तित कर सकता है, जो उसकी कुल राष्ट्रीय शक्ति का एक अभिन्न अंग है।

190. (B) प्रयुक्त हथियारों का प्रकार और संभावित विनाश का पैमाना।
पारंपरिक युद्ध और परमाणु युद्ध के बीच का सबसे बड़ा अंतर उनकी विनाशक शक्ति में निहित है। पारंपरिक युद्ध में तोप, टैंक और मिसाइलों जैसे हथियारों का प्रयोग होता है जिसका प्रभाव सीमित और भौगोलिक होता है। इसके विपरीत, परमाणु युद्ध में परमाणु हथियारों का उपयोग किया जाता है जो न केवल पूरे शहरों को तत्क्षण राख कर सकते हैं, बल्कि विकिरण के

NODIA

लिए एक ठोस रणनीतिक और राजनीतिक ढांचा प्रदान करता है।

240. (D) विरोधी गुट के विरुद्ध एक सामूहिक रक्षा बनाना।
शीतयुद्ध के दौरान गठबंधनों का निर्माण विशुद्ध रूप से सुरक्षा और शक्ति संतुलन की आवश्यकता से प्रेरित था। जब विश्व दो महाशक्ति गुटों में बंट गया, तो छोटे और मध्यम राज्यों ने महसूस किया कि अकेले वे किसी भी महाशक्ति के दबाव या आक्रमण को नहीं झेल पाएंगे। इसलिए, उन्होंने अपनी सैन्य शक्ति को मिलाकर साझा रक्षा प्रणालियाँ बनाईं। इन गठबंधनों का मुख्य उद्देश्य शत्रु को यह जताना था कि किसी एक सदस्य पर हमला करने का अर्थ पूरे गुट से युद्ध मोल लेना होगा। यह सामूहिक निवारण की एक रणनीति थी जिसने प्रत्यक्ष महाशक्ति संघर्ष को रोकने में मदद की।

241. (A) राष्ट्रीय हित सदैव विशुद्ध रूप से नैतिक और परोपकारी शब्दों में परिभाषित किया जाता है।
राष्ट्रीय हित के बारे में यह कहना गलत होगा कि वह सदैव नैतिक या परोपकारी होता है। वास्तव में, राष्ट्रीय हित अक्सर 'यथार्थवादी' और 'स्वार्थी' होता है, जो राष्ट्र की अपनी सुरक्षा, आर्थिक लाभ और राजनीतिक शक्ति को प्राथमिकता देता है। यद्यपि राज्य अपनी नीतियों को नैतिक आवरण में पेश करते हैं, लेकिन उनका मूल उद्देश्य अपने अस्तित्व की रक्षा और समृद्धि सुनिश्चित करना होता है। राष्ट्रीय हित की परिभाषा समय, विचारधारा और वैश्विक परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है, लेकिन वह सदैव राष्ट्र के आत्म-कल्याण पर केंद्रित होती है।

242. (B) व्यवस्थागत युद्ध
व्यवस्थागत युद्ध वह संघर्ष है जो न केवल दो देशों के बीच होता है, बल्कि जिसमें दुनिया की अधिकांश महान शक्तियाँ शामिल हो जाती हैं। ऐसा युद्ध पूरी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की नींव को हिला देता है और इसके अंत के बाद एक नई वैश्विक व्यवस्था और शक्ति संतुलन का उदय होता है। उदाहरण के लिए, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध व्यवस्थागत युद्ध थे जिन्होंने पुरानी साम्राज्यों को मिटा दिया और नए वैश्विक संस्थानों एवं महाशक्तियों को जन्म दिया। ये युद्ध तब होते हैं जब शक्ति का वितरण असंतुलित हो जाता है और पूरी प्रणाली में परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की जाती है।

243. (C) आदर्शवादी
शीतयुद्ध की समाप्ति के बाद एक 'नई विश्व व्यवस्था' का विचार, जो शांति, सामूहिक सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय कानून की सर्वोच्चता पर आधारित हो, पूरी तरह से आदर्शवादी विचारधारा की अभिव्यक्ति था। यह विचारधारा मानती है कि शक्ति के संघर्ष के युग को अब पीछे छोड़ा जा सकता है और संयुक्त राष्ट्र जैसे संस्थानों के माध्यम से एक न्यायपूर्ण वैश्विक समुदाय बनाया जा सकता है। यह दृष्टिकोण राष्ट्रों के बीच सहयोग के नए अवसरों और विधिक मर्यादाओं को प्राथमिकता देता है। यह विश्वास कि लोकतांत्रिक मूल्य और विधिक नियम युद्ध को समाप्त कर सकते हैं, इस आधुनिक विजन की मुख्य प्रेरक शक्ति रही है।

244. (D) सुरक्षा दुविधा
सुरक्षा दुविधा उस स्थिति को स्पष्ट करती है जहाँ राज्यों के बीच अविश्वास और अनिश्चितता इतनी अधिक होती है कि एक राज्य का रक्षात्मक कदम दूसरे को डरा देता है। जब कोई राष्ट्र अपनी रक्षा के लिए सैन्य शक्ति बढ़ाता है, तो पड़ोसी उसे आक्रामक तैयारी मान लेते हैं और वे भी जवाबी कार्रवाई में हथियार जुटाना शुरू कर देते हैं। इस चक्र के परिणामस्वरूप, अधिक हथियार होने के बावजूद सभी पक्ष स्वयं को पहले से अधिक असुरक्षित अनुभव करते हैं। यह अराजक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का एक कड़वा सच है, जहाँ अपनी सुरक्षा बढ़ाने का प्रयास अक्सर सामूहिक असुरक्षा और अवांछित शस्त्रों की दौड़ की ओर ले जाता है।

245. (A) इट यह संचार, वार्ता और समझौते का प्राथमिक साधन है।
विवादों के शांतिपूर्ण समाधान में कूटनीति की भूमिका अपरिहार्य है क्योंकि यह संवाद के रास्ते खुले रखती है। जब राष्ट्रों के बीच मतभेद पैदा होते हैं, तो कूटनीति ही वह मंच प्रदान करती है जहाँ दोनों पक्ष अपनी चिंताओं को साझा कर सकते हैं और एक साझा आधार खोज सकते हैं। यह अविश्वास को कम करने, गलतफहमियों को स्पष्ट करने और एक ऐसा समझौता करने में मदद करती है जिससे दोनों पक्षों के हितों की रक्षा हो सके। कूटनीति सैन्य बल का एक सभ्य और तर्कसंगत विकल्प है जो यह सुनिश्चित करता है कि मतभेद युद्ध में न बदलें और शांति बनी रहे।

246. (B) संप्रभुता
संप्रभुता का अर्थ है राज्य की वह सर्वोच्च कानूनी शक्ति जो उसे अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करती है। इसका तात्पर्य है कि कोई भी विदेशी शक्ति उस राज्य को आदेश नहीं दे सकती या उसके घरेलू निर्णयों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। संप्रभुता ही राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक स्वतंत्र इकाई के रूप में पहचान दिलाती है। यद्यपि आधुनिक वैश्वीकरण और अंतर्राष्ट्रीय कानून ने इसे कुछ हद तक सीमित किया है, फिर भी यह राज्य के अस्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण आधार बनी हुई है। संप्रभुता का अर्थ ही बाहरी नियंत्रण से मुक्ति और आत्मनिर्णय का अधिकार है।

247. (C) विचारधाराएँ
शीतयुद्ध मौलिक रूप से केवल दो देशों के बीच की शक्ति की लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह दो विरोधी जीवन दर्शनों और सामाजिक व्यवस्थाओं का महासंग्राम था। एक तरफ पश्चिमी गुट उदारवादी लोकतंत्र और पूंजीवाद का समर्थन कर रहा था, तो दूसरी तरफ पूर्वी गुट साम्यवाद और समाजवादी ढांचे को सर्वोपरि मानता था। विचारधारा ने न केवल इन राष्ट्रों की घरेलू नीतियों को प्रभावित किया, बल्कि यह भी तय किया कि विश्व भर में मित्र और शत्रु कौन होंगे। इस वैचारिक कट्टरता ने ही शीतयुद्ध को इतना लंबा, तनावपूर्ण और वैश्विक बना दिया, जहाँ प्रत्येक पक्ष अपनी व्यवस्था की श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए प्रयासरत था।

Click Here to Buy book on Amazon

जन्म दिया है, जो दर्शाते हैं कि विचार कैसे हिंसा को प्रेरित कर सकते हैं।

199. (C) कथन I सत्य है, लेकिन कथन II असत्य है।
राष्ट्रीय हित एक गतिशील अवधारणा है जो बदलती वैश्विक परिस्थितियों, नई तकनीक और उभरते सुरक्षा खतरों के अनुसार स्वतः को ढालती रहती है। कथन II गलत है क्योंकि राष्ट्रीय हित को बढ़ावा देने के लिए केवल सैन्य माध्यम ही एकमात्र साधन नहीं हैं। वास्तव में, आधुनिक युग में कूटनीति, आर्थिक निवेश, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में सक्रिय भागीदारी जैसे 'मृदु शक्ति' के उपकरण अधिक प्रभावी सिद्ध हो रहे हैं। सैन्य बल का उपयोग अक्सर अंतिम विकल्प के रूप में किया जाता है, जबकि शांतिपूर्ण माध्यम निरंतर आधार पर राष्ट्र के हितों की रक्षा करते हैं।

200. (D) 1, 2 और 3
अंतर्राष्ट्रीय कानून में राज्यों के अधिकार उनके कर्तव्यों के साथ गहराई से जुड़े हुए हैं। एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में, प्रत्येक राज्य का यह मौलिक कर्तव्य है कि वह अन्य राज्यों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करे। साथ ही, वैश्विक शांति के लिए यह अनिवार्य है कि सभी राष्ट्र अपने मतभेदों को केवल शांतिपूर्ण माध्यमों से सुलझाएं और किसी भी स्थिति में अनाधिकृत बल प्रयोग से बचें। ये तीनों कर्तव्य मिलकर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के विधिक ढांचे का निर्माण करते हैं, जो अराजकता को नियंत्रित कर राष्ट्रों के बीच शांतिपूर्ण और न्यायपूर्ण सह-अस्तित्व की संभावना सुनिश्चित करते हैं।

201. (A) आदर्शवाद
आदर्शवादी दृष्टिकोण का यह मानना है कि यद्यपि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था अराजक है, फिर भी मनुष्य अपने विवेक और सहयोग की भावना से ऐसे संस्थानों का निर्माण कर सकता है जो इस अराजकता को नियंत्रित कर सकें। आदर्शवादियों के अनुसार, नियम, मानदंड और साझा मूल्य अनिश्चितता को कम करते हैं और राष्ट्रों के बीच विश्वास पैदा करते हैं। वे तर्क देते हैं कि संस्थागत ढांचा राज्यों को केवल स्वार्थ के बजाय सामूहिक कल्याण के लिए काम करने हेतु प्रेरित कर सकता है। यह विचारधारा शक्ति की राजनीति के स्थान पर नियम-आधारित सहयोग और कूटनीतिक संवाद को शांति का सर्वोत्तम मार्ग मानती है।

202. (B) जातीय विवादों सहित अंतः-राज्यीय संघर्ष।
शीतयुद्ध की समाप्ति के बाद द्विध्रुवीय विश्व की कठोर स्थिरता समाप्त हो गई, जिससे कई क्षेत्रों में लंबे समय से दबे हुए आंतरिक तनाव उभर आए। इसके परिणामस्वरूप, राष्ट्रों के बीच होने वाले पारंपरिक युद्धों के स्थान पर देशों के भीतर होने वाले जातीय, धार्मिक और सांस्कृतिक संघर्षों में भारी वृद्धि हुई। यूगोस्लाविया, रवांडा और मध्य पूर्व के कई देशों में पहचान की राजनीति के कारण हुए गृहयुद्ध इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। ये संघर्ष अक्सर अत्यधिक हिंसक होते हैं और इनमें मानवीय संकट के साथ-साथ क्षेत्रीय अस्थिरता का खतरा भी बना रहता है, जो आधुनिक सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती है।

203. (C) राष्ट्रीय हित का प्रचार।
किसी भी राज्य की विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा और उनका प्रचार करना होता है। इस कार्य के लिए वह अपने राजनयिक कोर, गुप्तचर एजेंसियों और सेना का उपयोग एक औजार के रूप में करता है। ये सभी संस्थाएं मिलकर राष्ट्र की कुल शक्ति का निर्माण करती हैं। कूटनीति जहाँ वार्ता के माध्यम से हितों को साधती है, वहीं सेना अंतिम विकल्प के रूप में सुरक्षा सुनिश्चित करती है। इन साधनों का प्रभावी समन्वय ही किसी राष्ट्र को वैश्विक स्तर पर सफल और प्रभावशाली बनाता है।

204. (D) मृदु शक्ति
मृदु शक्ति का तात्पर्य सैन्य आक्रमण या आर्थिक रिश्वत के बिना दूसरों को अपने विचारों और लक्ष्यों के प्रति आकर्षित करने की क्षमता है। जब कोई देश अपनी संस्कृति, राजनीतिक मूल्यों, न्यायपूर्ण नीतियों और मानवीय छवि के माध्यम से विश्व भर में सम्मान और प्रभाव प्राप्त करता है, तो वह वास्तव में मृदु शक्ति का उपयोग कर रहा होता है। यह 'आकर्षण की शक्ति' है जो अन्य राष्ट्रों को स्वेच्छा से सहयोग करने के लिए प्रेरित करती है। आधुनिक युग में, मृदु शक्ति राष्ट्र की दीर्घकालिक प्रतिष्ठा बनाने और बिना किसी संघर्ष के अपने राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने का एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं प्रभावी उपकरण है।

205. (C) कथित गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन
यद्यपि गैर-हस्तक्षेप अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक बुनियादी सिद्धांत है, लेकिन आधुनिक युग में 'मानवीय हस्तक्षेप' के नाम पर इसमें अपवादों की चर्चा तेज हुई है। जब किसी देश के भीतर नरसंहार, जातीय संहार या गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन होते हैं, तो यह तर्क दिया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकता। ऐसे मामलों में संप्रभुता के अधिकार को मानवता की रक्षा के कर्तव्य से कमतर माना जाता है। हालांकि, यह अभी भी एक अत्यंत विवादित विषय है क्योंकि हस्तक्षेप का उपयोग कभी-कभी शक्तिशाली राष्ट्र अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए भी कर सकते हैं, जिससे कानून और नैतिकता के बीच संघर्ष बना रहता है।

206. (A) प्रबंधित; समाप्त
शस्त्र नियंत्रण और निरस्त्रीकरण दोनों शांति स्थापना के मार्ग हैं, लेकिन उनके तरीके अलग हैं। शस्त्र नियंत्रण का प्राथमिक उद्देश्य हथियारों की प्रतिस्पर्धा से उत्पन्न होने वाले युद्ध के 'जोखिम को प्रबंधित' करना और उसे एक नियंत्रित सीमा के भीतर रखना है। इसके विपरीत, निरस्त्रीकरण एक अधिक क्रांतिकारी लक्ष्य है जो हथियारों के भंडार को 'समाप्त' करने या उनकी संख्या में भारी कटौती करने पर बल देता है। सरल शब्दों में, शस्त्र नियंत्रण सुरक्षा दुविधा के बीच एक प्रकार का विधिक संतुलन और पूर्वानुमान बनाने का प्रयास करता है, जबकि निरस्त्रीकरण संघर्ष के भौतिक साधनों को ही जड़ से खत्म करने की वकालत करता है।

207. (D) निर्णय-प्रक्रिया दृष्टिकोण
निर्णय-प्रक्रिया दृष्टिकोण इस विचार पर आधारित है कि अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं केवल भौतिक शक्ति का परिणाम नहीं

NODIA

और विदेश नीति की स्वायत्तता को सुरक्षित रखने का एक सक्रिय कूटनीतिक प्रयास है। इसका उद्देश्य महाशक्तियों के सैन्य टकरावों से बचकर अपने राष्ट्रीय विकास पर ध्यान केंद्रित करना और अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है। यह विशेष रूप से शीतयुद्ध के दौरान उभरा एक सशक्त विकल्प था जिसने नव-स्वतंत्र राष्ट्रों को वैश्विक राजनीति में अपनी पहचान बनाए रखने में मदद की।

257. (D) हस्तक्षेप बलपूर्वक होता है, जबकि कूटनीति वार्ता पर आधारित होती है।
कूटनीति और हस्तक्षेप के बीच का मुख्य अंतर 'सहमति' और 'बल' में निहित है। कूटनीति वार्ता, अनुनय और आपसी समझौते के माध्यम से विवादों को सुलझाने का एक शांतिपूर्ण मार्ग है जिसमें सभी पक्ष स्वेच्छा से भाग लेते हैं। इसके विपरीत, हस्तक्षेप का अर्थ है किसी अन्य राज्य की इच्छा के विरुद्ध उसके आंतरिक मामलों में जबरदस्ती या दबाव के साथ प्रवेश करना। हस्तक्षेप अक्सर संप्रभुता का उल्लंघन माना जाता है और संघर्ष को जन्म देता है, जबकि कूटनीति का पूरा उद्देश्य ही युद्ध को टालना और आपसी सहयोग के माध्यम से राष्ट्रों के बीच मधुर संबंध स्थापित करना होता है।

258. (A) व्यवस्था दृष्टिकोण
व्यवस्था दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक 'संपूर्ण इकाई' के रूप में देखता है जहाँ राज्यों के बीच की अंतःक्रियाएं एक निश्चित संरचना के भीतर होती हैं। यह दृष्टिकोण यह विश्लेषण करता है कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के नियम, ध्रुवीयता और शक्ति का वितरण व्यक्तिगत राज्यों के विकल्पों को प्रतिबंधित और प्रभावित करते हैं। यहाँ राज्य को एक स्वतंत्र इकाई के बजाय पूरी व्यवस्था के एक भाग के रूप में देखा जाता है। जैसे एक मशीन के पुर्जे उसके ढांचे के अनुसार कार्य करते हैं, वैसे ही राज्य भी वैश्विक व्यवस्था के दबावों और संरचनात्मक बाधाओं के प्रति प्रतिक्रिया देते हैं।

259. (C) अन्य राज्य इसके विरुद्ध संतुलन बनाने के लिए कार्य कर सकते हैं, और इसके उपयोग में लागत आती है।
अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कोई भी राज्य इतना शक्तिशाली नहीं हो सकता कि उसकी शक्ति पर कोई अंकुश न हो। शक्ति की सबसे बड़ी सीमा 'शक्ति संतुलन' है, जहाँ अन्य राष्ट्र एक अत्यधिक शक्तिशाली राज्य के विरुद्ध गठबंधन बना लेते हैं। इसके अतिरिक्त, शक्ति का प्रयोग सैन्य हताहतों और भारी आर्थिक व्यय के रूप में उच्च लागत के साथ आता है, जो किसी भी देश की क्षमता को सीमित कर देता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून, विश्व जनमत और अपने ही देश का घरेलू विरोध भी शक्ति के स्वेच्छाचारी प्रयोग पर प्रभावी नियंत्रण रखते हैं। अतः शक्ति सदैव सापेक्ष और सीमाओं के अधीन होती है।

260. (D) 1, 2 और 3
युद्ध एक अत्यंत जटिल घटना है जिसके पीछे अनेक कारण हो सकते हैं जो अक्सर आपस में गुंथे होते हैं। मूर्त संसाधनों जैसे भूमि और तेल के लिए संघर्ष पारंपरिक रूप से युद्ध का मुख्य कारण रहा है। वैचारिक मतभेद, जैसे शीतयुद्ध के दौरान लोकतंत्र और साम्यवाद के बीच की लड़ाई, वैश्विक अशांति पैदा करते हैं। इसके अतिरिक्त, जातीय और धार्मिक तनाव भी आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों को जन्म देते हैं, जहाँ समूह अपनी पहचान और स्वायत्तता के लिए लड़ते हैं। अतः युद्ध को समझने के लिए इन सभी भौगोलिक, वैचारिक और सामाजिक-सांस्कृतिक पहलुओं का समग्र विश्लेषण अत्यंत आवश्यक है।

261. (D) परमाणु हथियार
निवारण की अवधारणा आधुनिक समय में मुख्य रूप से परमाणु हथियारों के साथ जुड़ी है। इन हथियारों की अत्यधिक विनाशकारी क्षमता ने एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी है जहाँ कोई भी हमलावर जानता है कि आक्रमण का परिणाम उसका अपना भी पूर्ण विनाश होगा। इसे 'परस्पर सुनिश्चित विनाश' कहा जाता है। पारंपरिक हथियार युद्ध जीतने के काम आते हैं, लेकिन परमाणु हथियार 'युद्ध न होने देने' के साधन के रूप में देखे जाते हैं। यह भय पर आधारित एक ऐसी रणनीतिक स्थिरता है जिसने परमाणु युग में बड़ी शक्तियों के बीच सीधे टकराव को रोकने में निर्णायक भूमिका निभाई है।

262. (B) राज्यों के ऊपर किसी केंद्रीय सत्ता की अनुपस्थिति
यथार्थवादी सिद्धांत में 'अराजकता' का अर्थ कोई हिंसक दंगा या पूर्ण अव्यवस्था नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी 'विधिक शून्यता' को दर्शाता है जहाँ राज्यों के ऊपर शासन करने वाली कोई सर्वोच्च विश्व सरकार या वैश्विक पुलिस बल नहीं है। चूंकि प्रत्येक राज्य संप्रभु है, इसलिए कोई भी उसे आदेश देने का कानूनी अधिकार नहीं रखता। इस अराजक संरचना के कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में 'स्वयं-सहायता' का सिद्धांत लागू होता है, जहाँ प्रत्येक राष्ट्र अपनी सुरक्षा के लिए स्वयं जिम्मेदार है। यही अराजकता राज्यों के बीच अविश्वास और निरंतर शक्ति संघर्ष का मुख्य संरचनात्मक कारण मानी जाती है।

263. (C) निरस्त्रीकरण या शस्त्र नियंत्रण
जब राष्ट्र सामूहिक रूप से जैविक हथियारों जैसे घातक अमानवीय शस्त्रों के उत्पादन और भंडारण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय लेते हैं, तो यह निरस्त्रीकरण और शस्त्र नियंत्रण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जैविक हथियार कन्वेंशन जैसी संधियाँ इसी उद्देश्य से बनाई गई हैं कि मानवता को विनाशकारी रोगों के हथियार के रूप में उपयोग से बचाया जा सके। यह दर्शाता है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और राज्यों की सामूहिक इच्छाशक्ति युद्ध की विनाशकता को कम करने के लिए प्रभावी नियम बना सकती है। यह सहयोग शस्त्रों की होड़ को रोकने और एक सुरक्षित वैश्विक वातावरण बनाने के लिए अत्यंत अनिवार्य है।

264. (C) कथन I सत्य है, लेकिन कथन II असत्य है।
गठबंधन राज्यों के बीच वह औपचारिक समझौता है जिसमें वे एक-दूसरे को सैन्य सहायता देने और साझा सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने की प्रतिबद्धता जताते हैं। कथन II गलत है क्योंकि गुटनिरपेक्षता की नीति गठबंधन का स्वरूप नहीं, बल्कि उनसे 'दूरी' बनाए रखने की नीति है। गुटनिरपेक्षता का अर्थ ही यह है कि कोई राज्य किसी महाशक्ति के नेतृत्व वाले सैन्य गुट का हिस्सा नहीं बनेगा। जहाँ गठबंधन सामूहिक सैन्य शक्ति बढ़ाने पर जोर देते हैं, वहीं गुटनिरपेक्षता स्वतंत्र विदेश

Downloaded from www.pdf.tube

281. (C) महाशक्तियों के बीच तनाव में कमी और बेहतर राजनयिक संबंध।
'देतांत' फ्रांसीसी शब्द है जिसका अर्थ है तनाव में ढील। शीतयुद्ध के संदर्भ में, यह 1970 के दशक की उस अवधि को दर्शाता है जब संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ ने अपने कड़वे संबंधों को सुधारने और परमाणु युद्ध के खतरे को कम करने के लिए सक्रिय प्रयास किए थे। इस दौरान कई महत्वपूर्ण शस्त्र नियंत्रण संधियों पर हस्ताक्षर हुए और कूटनीतिक संवाद बढ़ा। यह प्रत्यक्ष टकराव के स्थान पर शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की ओर एक कदम था। यद्यपि यह स्थायी शांति नहीं थी, लेकिन इसने शीतयुद्ध की कठोरता को कम करने और वैश्विक स्थिरता को कुछ समय के लिए मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

282. (A) घरेलू
यद्यपि राष्ट्रीय हित का क्रियान्वयन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है, लेकिन इसका निर्धारण अनिवार्य रूप से एक घरेलू प्रक्रिया है। यह किसी देश के भीतर की राजनीतिक व्यवस्था, वहां की सरकार की विचारधारा, आर्थिक जरूरतों, ऐतिहासिक अनुभवों और जनमत की आकांक्षाओं का परिणाम होता है। नीति निर्माता अपने देश की आंतरिक स्थिति और जनता के कल्याण को ध्यान में रखकर ही यह तय करते हैं कि राष्ट्र की प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए। इसलिए, राष्ट्रीय हित कोई बाहरी वस्तु नहीं है जिसे विश्व समाज थोपता है, बल्कि यह राष्ट्र के भीतर से उपजी वह दृष्टि है जो उसकी विदेश नीति के लक्ष्यों को परिभाषित करती है।

283. (D) आदर्शवाद
आदर्शवादी दृष्टिकोण का यह दृढ़ विश्वास है कि युद्ध कोई अनिवार्य बुराई नहीं है, बल्कि इसे मानवीय प्रयासों और संस्थागत सुधारों से समाप्त किया जा सकता है। आदर्शवादियों के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र जैसे संगठनों को सशक्त करना और मानवाधिकारों के प्रति वैश्विक प्रतिबद्धता बढ़ाना ही शांति का एकमात्र मार्ग है। वे तर्क देते हैं कि जब राज्य एक साझा कानूनी ढांचे और नैतिक मानदंडों के तहत कार्य करते हैं, तो उनकी स्वार्थपूर्ण और हिंसक प्रवृत्तियां नियंत्रित हो जाती हैं। यह विचारधारा शक्ति की राजनीति के स्थान पर वैश्विक सहयोग, न्याय और कानून के शासन को अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का नियामक बनाने की प्रबल वकालत करती है।

284. (A) P-3, Q-4, R-1, S-2
संप्रभुता राज्य के अपने क्षेत्र के भीतर सर्वोच्च अधिकार का प्रतिनिधित्व करती है, जो किसी बाहरी हस्तक्षेप को नकारती है। हस्तक्षेप का तात्पर्य किसी दूसरे राज्य के मामलों में अनपेक्षित और अक्सर बलपूर्वक प्रवेश से है। गठबंधन दो या दो से अधिक राज्यों के बीच की वह पारस्परिक रक्षा प्रतिबद्धता है जो सामूहिक सुरक्षा पर आधारित होती है। निरस्त्रीकरण का सीधा अर्थ हथियारों के भंडार को कम करने या उन्हें पूरी तरह समाप्त करने के प्रयासों से है। ये चारों अवधारणाएं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और कानून की रूपरेखा तैयार करती हैं, जो क्रमशः राज्य की स्वतंत्रता, संघर्ष, सामूहिक सुरक्षा और शांति स्थापना के विभिन्न पहलुओं को परिभाषित करती हैं।

285. (C) विचारधारा
विचारधारा राष्ट्रों को एक ऐसा विश्वदृष्टिकोण प्रदान करती है जो उनके लक्ष्यों और कार्यों को नैतिक आधार पर परिभाषित करता है। जब कोई राष्ट्र स्वयं को स्वतंत्र विश्व के रक्षक के रूप में देखता है, तो वह वास्तव में अपनी विदेश नीति को एक वैचारिक मिशन में बदल देता है। यह विचारधारा यह तय करती है कि राष्ट्र अपने मित्रों और विरोधियों को किस नजरिए से देखेगा और अपने संसाधनों का उपयोग किन आदर्शों के प्रचार के लिए करेगा। यह राष्ट्रीय हित को केवल भौतिक सुरक्षा से ऊपर उठाकर उसे एक उच्च नैतिक या राजनीतिक उद्देश्य प्रदान करती है, जो कूटनीति को गहराई से प्रभावित करता है।

286. (B) अधिनिर्णय का परिणाम एक बाध्यकारी निर्णय होता है, जबकि मध्यस्थता एक सुगम वार्ता है।
विवाद निपटान की इन दोनों पद्धतियों के बीच मुख्य अंतर निर्णय की बाध्यकारिता में है। मध्यस्थता में एक तीसरा पक्ष केवल समाधान के लिए सुझाव देता है और पक्षों को वार्ता के लिए राजी करता है, लेकिन वह अपना फैसला थोप नहीं सकता। इसके विपरीत, अधिनिर्णय या न्यायिक समाधान में मामला एक अदालत को सौंपा जाता है, जो दोनों पक्षों को सुनने के बाद एक विधिक फैसला देती है। यह फैसला अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत दोनों पक्षों पर अनिवार्य रूप से बाध्यकारी होता है। सरल शब्दों में, मध्यस्थता समझौता कराने का प्रयास है, जबकि अधिनिर्णय न्याय देने और विवाद को विधिक रूप से समाप्त करने की प्रक्रिया है।

287. (D) वैश्वीकरण
शीतयुद्ध के अंत और सोवियत संघ के विघटन के साथ ही वह द्विध्रुवीय पर्दा गिर गया जिसने दशकों तक दुनिया को बांटा था। इसके तुरंत बाद वैश्वीकरण एक नई वैश्विक शक्ति के रूप में उभरा, जिसने राष्ट्रों के बीच आर्थिक, तकनीकी और सांस्कृतिक दूरियों को तेजी से मिटाना शुरू किया। अब राष्ट्रों के बीच संबंध केवल सैन्य शक्ति पर नहीं, बल्कि सूचना के मुक्त प्रवाह, सीमा पार व्यापार और एकीकृत वैश्विक बाजारों पर आधारित होने लगे। वैश्वीकरण ने राष्ट्र-राज्य की पारंपरिक संप्रभुता को चुनौती दी और एक ऐसी परस्पर जुड़ी दुनिया बनाई जहाँ सहयोग और परस्पर निर्भरता ही आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की मुख्य पहचान बन गई है।

288. (B) अंतर्राष्ट्रीय कानून
क्षेत्रीय अखंडता का सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय कानून का वह मजबूत स्तंभ है जो किसी भी देश की भौगोलिक सीमाओं को बाहरी आक्रमण या परिवर्तन से सुरक्षा प्रदान करता है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ स्पष्ट रूप से यह घोषित करती हैं कि किसी राज्य के क्षेत्र के विरुद्ध बल प्रयोग करना अवैध है। यह नियम संप्रभुता के अधिकार का विस्तार है और राज्यों के बीच शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की गारंटी देता है। इसके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय कानून यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि कोई भी राष्ट्र अपनी सैन्य शक्ति का उपयोग करके

NODIA

273. (C) बोधित खतरे के विरुद्ध सामूहिक सुरक्षा प्रदान करना।
शीतयुद्ध के दौरान नाटो जैसे सैन्य गठबंधनों का गठन पूर्णतः 'सामूहिक सुरक्षा' के सिद्धांत पर आधारित था। इन संगठनों का प्राथमिक कारण एक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी से उत्पन्न होने वाला संभावित खतरा था। सदस्य राष्ट्रों ने यह समझौता किया कि किसी एक पर किया गया हमला सभी पर हमला माना जाएगा, जिससे संभावित आक्रमणकारी के मन में प्रतिशोध का भय पैदा हो सके। यह गठबंधन निर्माण शक्ति संतुलन का एक रणनीतिक प्रयास था जिसने छोटे और मध्यम राज्यों को महाशक्ति का संरक्षण प्रदान किया और एक व्यापक सुरक्षा कवच तैयार किया, जिससे प्रत्यक्ष युद्ध को रोकने में मदद मिली।

274. (D) एक अकेली महान शक्ति
'एकध्रुवीय' अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था वह स्थिति है जिसमें वैश्विक शक्ति का वितरण अत्यधिक असमान होता है और एक अकेली महाशक्ति सैन्य, आर्थिक और राजनीतिक रूप से अन्य सभी राष्ट्रों से कहीं आगे होती है। ऐसी व्यवस्था में वह महाशक्ति वैश्विक एजेंडा तय करने और नियमों को प्रभावित करने की अभूतपूर्व क्षमता रखती है। शीतयुद्ध की समाप्ति के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थिति को अक्सर इसी रूप में वर्णित किया गया है। यद्यपि ऐसी व्यवस्था में स्थिरता की संभावना होती है, लेकिन यह अन्य राज्यों के लिए संप्रभुता और स्वायत्तता की चुनौतियाँ भी पैदा करती है, क्योंकि शक्ति का कोई प्रभावी संतुलन मौजूद नहीं होता।

275. (A) आदर्शवादी
आदर्शवादी दृष्टिकोण का मूल मंत्र ही यही है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को शक्ति के संघर्ष के बजाय सहयोग और कानून के आधार पर संचालित किया जाना चाहिए। यह विचारधारा मानती है कि युद्ध और संघर्ष मानवीय प्रगति के लिए अनिवार्य नहीं हैं, बल्कि वे व्यवस्थागत दोषों का परिणाम हैं। आदर्शवादी एक ऐसे विश्व की वकालत करते हैं जहाँ नैतिक मूल्य, लोकतांत्रिक संस्थान और अंतर्राष्ट्रीय संगठन राष्ट्रों के व्यवहार को विनियमित करें। यह विश्वास कि सामूहिक कल्याण के लिए स्वार्थ का त्याग किया जा सकता है, आदर्शवाद की मुख्य प्रेरक शक्ति है जो न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण वैश्विक समाज की स्थापना का स्वप्न देखती है।

276. (B) जैव-रासायनिक युद्ध
जब किसी युद्ध में जहरीले रसायनों या रोगों को फैलाने वाले जैविक एजेंटों का उपयोग किया जाता है, तो उसे जैव-रासायनिक युद्ध कहा जाता है। मस्टर्ड गैस या क्लोरीन जैसे रसायनों का उपयोग इंसानों को सामूहिक रूप से मारने या अपंग करने के लिए किया जाता है। ये हथियार निर्दोष नागरिक आबादी और पर्यावरण पर विनाशकारी और अनियंत्रित प्रभाव डालते हैं, जिससे इनका उपयोग युद्ध के सबसे अमानवीय स्वरूपों में गिना जाता है। अपनी भयावहता के कारण, इन हथियारों को 'सामूहिक विनाश के हथियार' माना जाता है और अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत इनके निर्माण, भंडारण और उपयोग पर वैश्विक स्तर पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।

277. (C) अंतर्राष्ट्रीय कानून
अंतर्राष्ट्रीय कानून नियमों, सिद्धांतों और स्थापित प्रथाओं का वह व्यवस्थित समूह है जो संप्रभु राज्यों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय अभिनेताओं के आचरण को नियंत्रित करता है। यह राष्ट्रों के बीच संबंधों के लिए एक विधिक ढांचा प्रदान करता है, जिसमें संधियाँ, समुद्री कानून, मानवाधिकार और युद्ध के नियम शामिल हैं। यद्यपि इसमें घरेलू कानून की तरह कोई सर्वोच्च प्रवर्तन सत्ता नहीं है, फिर भी राज्य इसे अपनी आपसी सहमति, पारस्परिकता और व्यवस्था बनाए रखने की आवश्यकता के कारण बाध्यकारी मानते हैं। यह अराजक अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में नियमबद्धता और न्याय सुनिश्चित करने का सबसे महत्वपूर्ण विधिक उपकरण है।

278. (A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है।
निर्णय-प्रक्रिया दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन को एक नया आयाम देता है क्योंकि यह राज्य को केवल एक एकीकृत इकाई मानने से इनकार करता है। यह सूक्ष्म विश्लेषण करता है कि कैसे विदेश नीति के विकल्प वास्तव में सरकारी गलियारों के भीतर, विभिन्न मंत्रालयों के बीच की प्रतिस्पर्धा और व्यक्तिगत नेताओं की सोच के माध्यम से गढ़े जाते हैं। कारण स्पष्ट करता है कि क्यों यह दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है—क्योंकि यह राज्य के भीतर की जटिल मानवीय प्रक्रियाओं को उजागर करता है। अतः अभिकथन और कारण एक-दूसरे के पूरक हैं, जो दर्शाते हैं कि नीति निर्माण कोई सरल कार्य नहीं बल्कि एक आंतरिक संघर्ष है।

279. (D) मानकीय और प्रतिष्ठा संबंधी लागत
शक्ति का प्रयोग केवल भौतिक संसाधनों से सीमित नहीं होता, बल्कि यह प्रतिष्ठा और नैतिक मूल्यों से भी बंधा होता है। आधुनिक विश्व में, यदि कोई शक्तिशाली राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय कानून या मानवीय मानदंडों का घोर उल्लंघन करता है, तो उसे 'बहिष्कृत राज्य' बनने का खतरा रहता है। वैश्विक निंदा, कूटनीतिक अलगाव और सॉफ्ट पावर का नुकसान उस राज्य के दीर्घकालिक हितों को भारी क्षति पहुँचा सकता है। यह प्रतिष्ठा संबंधी लागत नेताओं को अपनी सैन्य शक्ति का स्वेच्छाचारी प्रयोग करने से रोकती है। अतः वैधता और सम्मान की इच्छा किसी भी संप्रभु राज्य की शक्ति पर एक अत्यंत प्रभावशाली मानकीय सीमा के रूप में कार्य करती है।

280. (A) जातीय विवाद और व्यापक अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष
आधुनिक युग में कई गृहयुद्ध केवल एक देश की आंतरिक समस्या नहीं रह गए हैं, बल्कि वे अक्सर बड़े क्षेत्रीय संकट में बदल जाते हैं। जब किसी देश में जातीय संघर्ष होता है, तो पड़ोसी देश अपने सजातीय समूहों की रक्षा के लिए या प्रमुख शक्तियाँ अपने रणनीतिक हितों के लिए उसमें कूद पड़ती हैं। इससे एक स्थानीय विवाद व्यापक युद्ध का रूप ले लेता है, जहाँ विदेशी हस्तक्षेप और परोक्ष युद्ध स्थिति को और अधिक जटिल बना देते हैं। यह दर्शाता है कि कैसे आंतरिक पहचान की लड़ाई और बाहरी शक्ति राजनीति आपस में जुड़कर वैश्विक शांति के लिए गंभीर खतरा पैदा करती हैं।

Click Here to Buy book on Amazon

30. क्षेत्रीय संगठनों के संबंध में सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए।
सूची I: (संगठन)
P. सार्क (SAARC)
Q. आसियान (ASEAN)
R. ओपेक (OPEC)
S. ओएएस (OAS)
सूची II: (प्राथमिक भौगोलिक केंद्र)
1. दक्षिण-पूर्व एशिया
2. पश्चिमी गोलार्ध
3. दक्षिण एशिया
4. मध्य पूर्व (मुख्य रूप से)
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:
(A) P-3, Q-1, R-4, S-2
(B) P-1, Q-3, R-2, S-4
(C) P-3, Q-2, R-4, S-1
(D) P-4, Q-1, R-2, S-3

31. मुख्य रूप किसके उत्तर में 2008 में जी-20 (G-20) को राष्ट्राध्यक्षों के शिखर सम्मेलन के स्तर तक बढ़ाया गया था?
(A) 9/11 के आतंकवादी हमले।
(B) वैश्विक वित्तीय संकट।
(C) जलवायु परिवर्तन वार्ता की आवश्यकता।
(D) यूरोपीय संघ का विस्तार।

32. क्षेत्रीय संगठनों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. आसियान के पास सुरक्षा संवाद के लिए 'आसियान क्षेत्रीय मंच' (ARF) नामक एक तंत्र है।
2. सार्क ने 'सारको' नामक एकल मुद्रा सफलतापूर्वक आरंभ की है।
3. जी-20 में विकसित और उभरती अर्थव्यवस्थाएं दोनों शामिल हैं।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3

33. संयुक्त राष्ट्र चार्टर की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस लक्ष्य और उद्देश्य का स्पष्ट उल्लेख किया गया है?
(A) सभी सदस्य देशों में लोकतंत्र को बढ़ावा देना।
(B) आने वाली पीढ़ियों को युद्ध की विभीषिका से बचाना।
(C) विधायी शक्तियों वाली एक विश्व सरकार स्थापित करना।
(D) अंतरराष्ट्रीय व्यापार और वित्त को विनियमित करना।

34. संयुक्त राष्ट्र संरचनात्मक रूप से कितने प्रमुख अंगों से बना है?
(A) चार
(B) पांच
(C) सात
(D) छह

35. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में लेबल किया गया है।
अभिकथन (A): संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की संरचना की कालदोषयुक्त और अप्रतिनिधिक होने के लिए आलोचना की गई है।
कारण (R): वीटो शक्ति वाले पांच स्थाई सदस्य द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के शक्ति वितरण को दर्शाते हैं, न कि 21वीं सदी के।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

36. संयुक्त राष्ट्र का कौन सा प्रमुख अंग संयुक्त राष्ट्र और उसकी विशिष्ट एजेंसियों के आर्थिक और सामाजिक कार्यों के समन्वय के लिए उत्तरदायी है?
(A) सुरक्षा परिषद
(B) महासभा
(C) आर्थिक और सामाजिक परिषद (ECOSOC)
(D) न्यास परिषद (Trusteeship Council)

37. संयुक्त राष्ट्र संघ के भीतर 'शक्ति संघर्ष और कूटनीति' किस अंग के कामकाज में सबसे स्पष्ट रूप से दिखाई देती है?
(A) अंतरराष्ट्रीय न्यायालय
(B) सचिवालय
(C) आर्थिक और सामाजिक परिषद
(D) सुरक्षा परिषद

38. संयुक्त राष्ट्र द्वारा 'शांति स्थापना' की अवधारणा:
(A) चार्टर में स्पष्ट रूप से नहीं है लेकिन एक कार्यात्मक उपकरण के रूप में विकसित हुई है।
(B) आधिकारिक संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय VII में स्पष्ट रूप से वर्णित है।
(C) केवल संयुक्त राष्ट्र महासभा के लिए आरक्षित एक विशिष्ट शक्ति है।
(D) पूरी तरह से सुरक्षा परिषद के पांच स्थाई सदस्यों द्वारा वित्तपोषित है।

39. संयुक्त राष्ट्र के वित्तपोषण के संबंध में एक प्रमुख मुद्दा है:
(A) इसके मुख्य बजट के लिए स्वैच्छिक योगदान पर अत्यधिक निर्भरता।
(B) विश्व बैंक द्वारा संयुक्त राष्ट्र को ऋण देने से मना करना।
(C) कुछ सदस्य देशों द्वारा निर्धारित अंशदान के भुगतान में देरी और भुगतान न करना।
(D) अपने शांति स्थापना अभियानों से अत्यधिक लाभ प्राप्त करना।

NODIA

दूसरे के भूभाग को नहीं हड़पेगा, जिससे वैश्विक व्यवस्था में स्थिरता और न्याय बना रहे।

289. (C) मूर्त
राष्ट्रीय शक्ति के उन तत्वों को मूर्त कहा जाता है जिन्हें भौतिक रूप से देखा, मापा और गिना जा सकता है। एक विशाल सेना, आधुनिक टैंक, लड़ाकू विमान और उन्नत हथियार प्रणालियाँ इसी श्रेणी में आती हैं क्योंकि वे राष्ट्र की प्रत्यक्ष सैन्य ताकत का ठोस प्रमाण हैं। ये तत्व युद्ध के समय और कूटनीतिक दबाव बनाने में सीधे तौर पर सहायक होते हैं। यद्यपि नेतृत्व और मनोबल जैसे अमूर्त तत्व भी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन मूर्त संसाधन ही वह भौतिक आधार तैयार करते हैं जिस पर राष्ट्र की सुरक्षा और शक्ति का पूरा ढांचा टिका होता है। यह किसी भी संप्रभु राज्य की रक्षात्मक और आक्रामक क्षमता का प्राथमिक मापदंड है।

290. (D) 1, 2 और 3
राष्ट्रीय हित एक बहुआयामी अवधारणा है जिसमें ये तीनों पहलू अनिवार्य रूप से शामिल होते हैं। सबसे प्राथमिक हित राष्ट्र का अस्तित्व और उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है, क्योंकि इसके बिना अन्य लक्ष्य अर्थहीन हैं। दूसरा महत्वपूर्ण स्तंभ राष्ट्र की आर्थिक उन्नति और समृद्धि है जो जनता के कल्याण के लिए आवश्यक है। अंततः, प्रत्येक राष्ट्र अपनी विशिष्ट विचारधारा और मूल्यों को भी वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देना चाहता है ताकि उसका सांस्कृतिक प्रभाव बढ़ सके। ये तीनों तत्व मिलकर किसी भी देश की विदेश नीति का मूल आधार बनाते हैं, जो समय के साथ निरंतर विकसित और अनुकूलित होते रहते हैं।

291. (A) महाशक्तियों के विरुद्ध गुटनिरपेक्ष राज्यों का वैश्विक गठबंधन
शीतयुद्ध की सबसे प्रमुख पहचान द्विध्रुवीयता, वैचारिक प्रतिस्पर्धा और शस्त्रों की दौड़ थी। यद्यपि गुटनिरपेक्ष आंदोलन शीतयुद्ध के दौरान उभरा, लेकिन इसे महाशक्तियों के विरुद्ध कोई वैश्विक सैन्य गठबंधन कहना गलत होगा। गुटनिरपेक्षता वास्तव में किसी भी सैन्य गुट का हिस्सा न बनने की नीति थी, न कि स्वयं कोई प्रतिद्वंद्वी सैन्य गुट बनाने की। यह आंदोलन उन देशों का एक कूटनीतिक मंच था जो अपनी संप्रभुता और स्वतंत्र पहचान बचाना चाहते थे। अतः गुटनिरपेक्षता ने शीतयुद्ध की संरचना में एक तीसरे विकल्प के रूप में कार्य किया, लेकिन उसने स्वयं को कभी एक प्रतिस्पर्धी सैन्य शक्ति के रूप में संगठित नहीं किया।

292. (D) निर्णय-प्रक्रिया दृष्टिकोण
निर्णय-प्रक्रिया दृष्टिकोण का मुख्य फोकस यह समझना है कि विदेश नीति कोई स्वचालित निर्णय नहीं है। यह अध्ययन करता है कि कैसे सरकार के भीतर मौजूद विभिन्न संस्थाएं—जैसे सेना, गुप्तचर विभाग और नागरिक मंत्रालय—अपने-अपने हितों के साथ नीति निर्माण को प्रभावित करती हैं। जब निर्णय इन समूहों के बीच सौदेबाजी या आपसी प्रतिस्पर्धा का परिणाम होता है, तो वह नौकरशाही राजनीति के दायरे में आता है। यह विश्लेषण राज्य की एकात्मक छवि को तोड़कर उसके भीतर की जटिल कार्यप्रणाली को उजागर करता है, जिससे यह पता चलता है कि वास्तविक निर्णय के पीछे कौन से आंतरिक दबाव और हित शामिल थे।

293. (B) एक संबंधात्मक अवधारणा, जो संदर्भ और शामिल अभिनेताओं पर निर्भर करती है।
अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में शक्ति कोई स्थिर वस्तु नहीं है जिसे केवल हथियारों की संख्या से मापा जा सके। यह वास्तव में एक संबंधात्मक अवधारणा है, जिसका अर्थ है कि एक राज्य की शक्ति इस पर निर्भर करती है कि वह दूसरे राज्य की तुलना में कितनी प्रभावी है और किस संदर्भ में उपयोग की जा रही है। एक राष्ट्र सैन्य रूप से शक्तिशाली हो सकता है लेकिन आर्थिक वार्ताओं में निर्बल हो सकता है। अतः शक्ति को सदैव उस विशिष्ट स्थिति और उन अभिनेताओं के संदर्भ में समझना चाहिए जिनके बीच प्रभाव डालने की प्रक्रिया चल रही है। यह संदर्भ के अनुसार बदलती रहने वाली एक गतिशील क्षमता है।

294. (C) संप्रभुता
संप्रभुता का विधिक अर्थ यह है कि प्रत्येक राज्य अपने क्षेत्र के भीतर सर्वोच्च है और कानून की दृष्टि में सभी राज्य समान हैं। इसी संप्रभु समानता से यह सिद्धांत निकलता है कि बराबर का कोई भी बराबर पर अधिकार क्षेत्र नहीं रखता। इसलिए, अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत एक राज्य दूसरे राज्य की घरेलू अदालतों में अभियोग चलाने के अधिकार क्षेत्र से मुक्त होता है। यह नियम राज्यों की गरिमा और स्वतंत्रता की रक्षा करता है और उन्हें बाहरी कानूनी दबाव के बिना अपने कार्यों को करने की अनुमति देता है। यह संप्रभुता का वह विधिक कवच है जो राष्ट्रों के बीच आपसी सम्मान और गैर-हस्तक्षेप की नींव को मजबूत करता है।

295. (D) व्यवस्था सिद्धांत
व्यवस्था सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विश्लेषण एक 'ब्लैक बॉक्स' मॉडल के रूप में करता है। इसके अनुसार, राज्यों का आंतरिक स्वरूप उनके व्यवहार को समझने के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है, जितना कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना और शक्ति का वितरण। जैसे बिलियर्ड गेंदों की गति मेज की सीमाओं और अन्य गेंदों से उनके टकराने से निर्धारित होती है, वैसे ही राज्यों के कार्य भी वैश्विक व्यवस्था के दबावों और शक्ति संतुलन द्वारा नियंत्रित होते हैं। यह दृष्टिकोण राज्य के भीतर झांकने के बजाय उस व्यापक संरचनात्मक ढांचे पर ध्यान केंद्रित करता है जो राष्ट्रों की चालों को सीमित और निर्देशित करता है।

296. (A) द्विपक्षीय; बहुपक्षीय
अंतर्राष्ट्रीय संधियों का वर्गीकरण उनमें शामिल पक्षों की संख्या के आधार पर किया जाता है। जब कोई समझौता केवल दो राष्ट्रों के बीच होता है, जैसे सीमा विवाद या व्यापारिक रियायत, तो उसे द्विपक्षीय संधि कहा जाता है। इसके विपरीत, जब किसी संधि में तीन या अधिक राज्य शामिल होते और वह अक्सर वैश्विक महत्व के मुद्दों को संबोधित करती है, तो उसे बहुपक्षीय संधि कहा जाता है। दोनों ही प्रकार की संधियाँ अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत समान रूप से बाध्यकारी होती हैं

NODIA

नीति और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की वकालत करती है। अतः ये दोनों अवधारणाएं सुरक्षा प्राप्त करने के दो विपरीत मार्ग प्रस्तुत करती हैं।

265. (A) अपने विदेश नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करना।
राष्ट्रीय हित को बढ़ावा देना किसी भी संप्रभु राज्य की विदेश नीति का मुख्य प्रेरक बल और अंतिम लक्ष्य होता है। इसमें वे सभी रणनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधी उद्देश्य शामिल हैं जो देश के अस्तित्व, कल्याण और विकास के लिए आवश्यक हैं। जब कोई राज्य कूटनीति करता है, व्यापारिक समझौते करता है या अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करता है, तो वह वास्तव में अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति का प्रयास कर रहा होता है। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जहाँ राष्ट्र बदलते वैश्विक परिदृश्य में अपने लाभ को अधिकतम करने और खतरों को न्यूनतम करने के लिए अपनी नीतियों को निरंतर अनुकूलित करते हैं।

266. (B) कूटनीति
कूटनीति राज्यों के बीच आधिकारिक प्रतिनिधियों के माध्यम से संबंधों के प्रबंधन की कला है। जब कोई देश अपने विदेश मंत्री या राजदूत को किसी अन्य देश के साथ वार्ता करने के लिए भेजता है, तो वह कूटनीतिक चैनलों का उपयोग कर रहा होता है। इसका उद्देश्य संवाद स्थापित करना, राष्ट्रीय हितों को शांतिपूर्वक प्राप्त करना और साझा समस्याओं का समाधान खोजना है। कूटनीति युद्ध का विकल्प है और यह दर्शाती है कि राष्ट्र अपने मतभेदों को तर्क और चर्चा के माध्यम से सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में स्थिरता और सहयोग को बढ़ावा देने का सबसे महत्वपूर्ण सभ्य माध्यम है।

267. (D) संप्रभु समान के रूप में राज्य
संप्रभु उन्मुक्ति का सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय कानून का वह नियम है जो यह मानता है कि एक संप्रभु राज्य दूसरे राज्य की अदालतों के अधिकार क्षेत्र के अधीन नहीं हो सकता। यह 'संप्रभु समानता' के विचार का सीधा परिणाम है—चूंकि सभी राज्य बराबर हैं, इसलिए कोई भी राज्य दूसरे का न्यायाधीश नहीं बन सकता। यह सिद्धांत राज्यों की स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा करता है और उन्हें बाहरी कानूनी हस्तक्षेप के बिना अपने कार्यों को संचालित करने की अनुमति देता है। यह नियम राष्ट्रों के बीच आपसी सम्मान और समानता के विधिक संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है।

268. (A) संचार सिद्धांत
संचार सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को सूचनाओं के आदान-प्रदान और उनके प्रसंस्करण के एक नेटवर्क के रूप में देखता है। यह दृष्टिकोण इस बात पर जोर देता है कि युद्ध अक्सर शत्रुतापूर्ण इरादों के बजाय गलत धारणाओं और सूचनाओं के त्रुटिपूर्ण प्रवाह के कारण होते हैं। यदि एक राज्य दूसरे के रक्षात्मक कदमों को आक्रामक समझने की त्रुटि करता है, तो अनपेक्षित संघर्ष शुरु हो सकता है। अतः यह सिद्धांत पारदर्शी संचार और स्पष्ट संकेतों के महत्व को रेखांकित करता है। इसका मानना है कि सूचना के चैनलों में सुधार करके और गलतफहमी दूर करके कई युद्धों को टाला जा सकता है।

269. (C) गुटनिरपेक्षता
गुटनिरपेक्षता की नीति का जन्म शीतयुद्ध के दौरान उभरे द्विध्रुवीय विश्व में महाशक्तियों के सैन्य गुटों से स्वतंत्र रहने के लिए हुआ था। 1991 में शीतयुद्ध के अंत और सोवियत संघ के पतन के साथ ही वह मुख्य वैचारिक और सैन्य टकराव समाप्त हो गया जिससे यह नीति प्रेरित थी। इसके परिणामस्वरूप, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता पर गंभीर प्रश्न उठे क्योंकि अब कोई 'ध्रुव' नहीं बचे थे जिनसे दूरी बनाई जाए। हालांकि, कई देशों ने इसे विकासशील राष्ट्रों के सामूहिक आर्थिक और राजनीतिक मंच के रूप में नया स्वरूप देने का प्रयास किया है, लेकिन इसकी मूल रणनीतिक स्थिति को वैश्वीकरण और नए शक्ति संतुलन ने बदल दिया है।

270. (A) 2, 1, 4, 3
अंतर्राष्ट्रीय संकट के समय राज्य आमतौर पर विवाद के क्रमिक बढ़ने के मार्ग को अपनाते हैं। सर्वप्रथम, राजनयिक विरोध और वार्ता के माध्यम से असहमति दर्ज की जाती है। यदि इससे स्थिति नहीं सुधरती, तो कूटनीतिक दबाव बढ़ाने के लिए राजनयिक संबंधों को विच्छेद किया जा सकता है। इसके बाद, अधिक कठोर कदम के रूप में आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाते हैं ताकि शत्रु की अर्थव्यवस्था पर दबाव बनाया जा सके। अंततः, जब सभी शांतिपूर्ण और दबावकारी उपाय विफल हो जाते हैं, तब अंतिम विकल्प के रूप में प्रत्यक्ष सैन्य बल या युद्ध का सहारा लिया जाता है। यह क्रम शक्ति के बढ़ते हुए प्रयोग को दर्शाता है।

271. (D) सैन्य और आर्थिक क्षमता
यथार्थवादी सिद्धांत के अनुसार, राष्ट्रीय शक्ति का सबसे विश्वसनीय और निर्णायक आधार उसकी सैन्य और आर्थिक क्षमता है। यथार्थवादियों का मानना है कि एक अराजक विश्व में, जहाँ सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है, केवल वे ही राज्य सुरक्षित रह सकते हैं जिनके पास शक्तिशाली सेना और उसे सहारा देने वाली मजबूत अर्थव्यवस्था है। सांस्कृतिक आकर्षण या नैतिक प्राधिकार 'मृदु शक्ति' के हिस्से हैं, लेकिन यथार्थवाद में इन्हें गौण माना जाता है। उनके अनुसार, अंतिम विश्लेषण में यह राज्य की भौतिक ताकत ही है जो उसके अस्तित्व की रक्षा करती है और उसे वैश्विक राजनीति में प्रभावशाली बनाती है।

272. (B) इसकी रोकथाम और उन्मूलन
आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय कानून का मुख्य दर्शन 'युद्ध का निषेध' है। इसका प्राथमिक लक्ष्य राष्ट्रों के बीच सशस्त्र संघर्ष की विभीषिका को रोकना और उसे पूरी तरह समाप्त करना है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के नियम राज्यों को बल प्रयोग करने से प्रतिबंधित करते हैं और उन्हें विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए विवश करते हैं। कानून का उद्देश्य एक ऐसी नियम-आधारित व्यवस्था बनाना है जहाँ हिंसा के स्थान पर न्याय और तर्क का शासन हो। यद्यपि युद्धों को पूरी तरह समाप्त करना कठिन सिद्ध हुआ है, फिर भी अंतर्राष्ट्रीय कानून का निरंतर प्रयास युद्ध के बहाने को कम करना और उसके विनाशकारी प्रभावों को विधिक रूप से सीमित करना है।

Downloaded from www.pdf.tube

अध्याय 08
अंतरराष्ट्रीय संबंध एवं भारतीय विदेश नीति

1. निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 'नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था' (NIEO) के प्राथमिक उद्देश्य को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है?
(A) विशेष रूप से विकसित देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौतों को बढ़ावा देना।
(B) विकासशील देशों के पक्ष में वैश्विक आर्थिक प्रणाली का पुनर्गठन करना।
(C) जी-7 (G7) द्वारा प्रबंधित एक नई वैश्विक मुद्रा स्थापित करना।
(D) अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) और विश्व बैंक जैसे सभी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को समाप्त करना।

2. अंतरराष्ट्रीय संबंधों की राजनीतिक अर्थव्यवस्था के संबंध में नीचे दो कथन दिए गए हैं।
कथन I: यह उनके राजनीतिक निहितार्थों पर विचार किए बिना केवल व्यक्तिगत राज्यों की आर्थिक नीतियों का अध्ययन करता है।
कथन II: यह अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में राजनीति (शक्ति) और अर्थव्यवस्था (धन) के बीच परस्पर क्रिया का विश्लेषण करता है।
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
(D) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।

3. निम्नलिखित में से कौन सी 'नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था' (NIEO) की मुख्य मांग नहीं है?
(A) कच्चे माल के लिए स्थिर और लाभकारी मूल्य सुरक्षित करना।
(B) उत्तर से दक्षिण को मिलने वाली विकास सहायता में वृद्धि करना।
(C) अपने प्राकृतिक संसाधनों पर विकासशील देशों की संप्रभुता को सीमित करना।
(D) विकसित देशों से विकासशील देशों को प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण को बढ़ावा देना।

4. 'उत्तर-दक्षिण संवाद' शब्द का प्रयोग मुख्य रूप से किन दो समूहों के बीच वार्ता का वर्णन करने के लिए किया जाता है?
(A) पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध के देश।
(B) नाटो (NATO) और पूर्व वारसॉ संधि के सदस्य देश।
(C) तेल निर्यातक देश और तेल आयातक देश।
(D) विकसित, औद्योगिक देश और विकासशील देश।

5. निम्नलिखित में से कौन सी 'दक्षिण-दक्षिण सहयोग' की एक प्रमुख विशेषता है?
(A) यह उत्तर-दक्षिण सहायता के समान दाता-प्राप्तकर्ता संबंध पर आधारित है।
(B) यह मुख्य रूप से विश्व बैंक जैसे अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रबंधित और वित्तपोषित है।
(C) इसमें राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में विकासशील देशों के बीच सहयोग शामिल है।
(D) यह विशेष रूप से दक्षिणी गोलार्ध के देशों के बीच सैन्य और सुरक्षा गठबंधनों पर केंद्रित है।

6. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में लेबल किया गया है।
अभिकथन (A): निर्भरता सिद्धांत विकास के आधुनिकीकरण सिद्धांतों की आलोचना के रूप में उभरा।
कारण (R): निर्भरता सिद्धांतकारों का तर्क है कि 'परिधि' का अल्पविकास 'केंद्र' के प्रभुत्व वाली पूंजीवादी विश्व प्रणाली में इसके एकीकरण का प्रत्यक्ष परिणाम है।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

7. विश्व व्यापार संगठन (WTO) का प्राथमिक कार्य क्या है?
(A) भुगतान संतुलन की समस्याओं वाले देशों को आपातकालीन ऋण प्रदान करना।
(B) तेल और गैस जैसी प्रमुख वस्तुओं की कीमतें निर्धारित करना।
(C) सदस्य देशों के लिए एक वैश्विक केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करना।
(D) अंतरराष्ट्रीय व्यापार को विनियमित करना और वाणिज्य के सुचारु प्रवाह को सुनिश्चित करना।

8. 'नव-उपनिवेशवाद' की अवधारणा को सबसे सटीक रूप से इस प्रकार वर्णित किया गया है:
(A) आर्थिक और सांस्कृतिक माध्यमों से किसी विकासशील देश पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण।
(B) किसी विदेशी शक्ति द्वारा संप्रभु क्षेत्र पर प्रत्यक्ष राजनीतिक और सैन्य अधिकार।
(C) द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व स्तर पर हुई कानूनी वि-उपनिवेशीकरण की औपचारिक प्रक्रिया।
(D) एक पूर्व उपनिवेश और उसके औपनिवेशिक शासक के

NODIA

और राज्यों के बीच विधिक सहयोग और स्थिरता का ढांचा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

297. (B) गठबंधन
2001 की घटनाओं के बाद जब कई देशों ने मिलकर आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध का संकल्प लिया, तो उन्होंने वास्तव में एक गठबंधन का निर्माण किया। यह गठबंधन पारंपरिक राज्यों के बजाय एक साझा गैर-राज्य खतरे के विरुद्ध सामूहिक सुरक्षा पर आधारित था। गठबंधन का उद्देश्य सैन्य क्षमताओं, खुफिया जानकारी और कूटनीतिक प्रभाव को साझा करना था ताकि साझा शत्रु को अधिक प्रभावी ढंग से पराजित किया जा सके। यह दर्शाता है कि आधुनिक युग में खतरे बदल गए हैं, लेकिन राष्ट्र अभी भी अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गठबंधन निर्माण के उस यथार्थवादी उपकरण का उपयोग करते हैं जो सामूहिक शक्ति के सिद्धांत पर टिका है।

298. (C) वैश्वीकरण
वैश्वीकरण की एक प्रमुख विशेषता राष्ट्रों की बढ़ती हुई आर्थिक परस्पर निर्भरता है। इसके अंतर्गत पूंजीवाद का वैश्विक प्रसार और बहुराष्ट्रीय कंपनियों की बढ़ती शक्ति ने एक ऐसा एकीकृत आर्थिक तंत्र बना दिया है जो राज्य की पारंपरिक सीमाओं को पार कर जाता है। अब राज्यों को अपनी आर्थिक नीतियां अक्सर वैश्विक बाजारों, निवेशकों और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों की माँगों के अनुसार ढालनी पड़ती हैं। यह प्रक्रिया राज्य की उस पुरानी अवधारणा को चुनौती देती है जिसमें वह अपने घरेलू मामलों पर पूर्ण संप्रभुता रखता था। वैश्वीकरण ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आधुनिक राज्य की शक्ति अब अकेले कार्य करने के बजाय वैश्विक आर्थिक नेटवर्क के साथ जुड़ने पर निर्भर है।

299. (D) सुरक्षा दुविधा और पारस्परिक संदेह
शस्त्रों की दौड़ का मूल कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की वह अराजक संरचना है जहाँ राज्यों के बीच गहरे अविश्वास की स्थिति बनी रहती है। जब एक राज्य अपनी सुरक्षा के लिए हथियार बढ़ाता है, तो दूसरा राज्य उसे संभावित हमलावर मानकर स्वयं भी सैन्य वृद्धि करने लगता है। इस सुरक्षा दुविधा के कारण अविश्वास का एक ऐसा चक्र शुरू होता है जहाँ प्रत्येक पक्ष केवल सुरक्षित रहने के प्रयास में हथियारों का अंबार लगाता जाता है। संदेह की यह मनोवैज्ञानिक स्थिति ही वह मुख्य इंजन है जो शस्त्रों की होड़ को चलाती है, जिससे शांति के बजाय अंतहीन सैन्य प्रतिस्पर्धा और तनाव की स्थिति बनी रहती है।

300. (B) आदर्शवादी परंपरा और संयुक्त राष्ट्र जैसे संगठन।
युद्ध की रोकथाम और उसके पूर्ण उन्मूलन का लक्ष्य आदर्शवादी विचारधारा की नींव है। आदर्शवादियों का मानना है कि केवल शक्ति संतुलन से शांति नहीं आ सकती, बल्कि इसके लिए एक ऐसी सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था चाहिए जहाँ सभी राष्ट्र मिलकर किसी भी आक्रामक राज्य को रोकने का संकल्प लें। संयुक्त राष्ट्र जैसे संगठनों की स्थापना इसी आदर्शवादी विजन के साथ की गई थी कि विवादों का समाधान बल प्रयोग के बजाय कानून और सामूहिक संस्थागत दबाव से किया जाए। यह दृष्टिकोण शक्ति की राजनीति के स्थान पर नियम-आधारित वैश्विक व्यवस्था और नैतिक सहयोग को शांति बनाए रखने का एकमात्र स्थायी मार्ग मानता है।

www.nodia.in

Click Here to Buy book on Amazon

अभिकथन (A): सार्क की प्रगति धीमी रही है और इसके सदस्यों के बीच राजनीतिक विवादों के कारण इसमें बाधा आई है।
कारण (R): सार्क चार्टर स्पष्ट रूप से द्विपक्षीय और विवादास्पद मुद्दों पर चर्चा करने से मना करता है।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

20. निम्नलिखित में से कौन दक्षिण-पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संगठन (आसियान) का संस्थापक सदस्य नहीं है?
(A) थाईलैंड
(B) फिलीपींस
(C) सिंगापुर
(D) वियतनाम

21. पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन (OPEC) किस प्रकार के अंतरराष्ट्रीय संगठन का उदाहरण है?
(A) एक सामूहिक सुरक्षा संगठन
(B) एक मानवाधिकार निगरानी समूह
(C) एक वस्तु उत्पादक संघ (कार्टेल)
(D) यूरोपीय संघ की तरह एक क्षेत्रीय एकीकरण परियोजना

22. अमेरिकी राज्यों के संगठन (OAS) का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?
(A) विभिन्न लैटिन अमेरिकी देशों के बीच पेट्रोलियम और ऊर्जा नीतियों का समन्वय करना।
(B) राजनीतिक चर्चा और पश्चिमी गोलार्ध के मामलों के लिए एक क्षेत्रीय मंच के रूप में कार्य करना।
(C) यूरोपीय संघ के मॉडल के आधार पर व्यापक आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देना।
(D) अमेरिकी महाद्वीप के संभावित बाहरी खतरों के विरुद्ध एक सामूहिक सैन्य गठबंधन के रूप में कार्य करना।

23. जी-20 (G-20) को सर्वोत्तम रूप से इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है:
(A) एक स्थाई सचिवालय और प्रवर्तन शक्तियों वाला एक औपचारिक अंतरराष्ट्रीय संगठन।
(B) 20 सबसे बड़े विकासशील देशों का गठबंधन।
(C) आतंकवाद विरोधी अभियान पर केंद्रित एक सैन्य समझौता।
(D) प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए एक प्रमुख मंच।

24. निम्नलिखित में से कौन सा आसियान (ASEAN) का प्राथमिक उद्देश्य है?
(A) क्षेत्र में आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना।
(B) दक्षिण-पूर्व एशिया के लिए एक एकल मुद्रा स्थापित करना।
(C) चीन के विरुद्ध सैन्य गठबंधन बनाना।
(D) ताड़ के तेल और रबर की वैश्विक कीमतों को नियंत्रित करना।

25. निम्नलिखित में से कौन सार्क (SAARC) का सदस्य नहीं है?
(A) भूटान
(B) मालदीव
(C) म्यांमार
(D) अफगानिस्तान

26. जी-20 (G-20) के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
(A) इसके सदस्य वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के लगभग 85% का प्रतिनिधित्व करते हैं।
(B) इसमें केवल विश्व के सबसे विकसित राष्ट्र शामिल हैं।
(C) यह मुख्य रूप से वैश्विक सुरक्षा मुद्दों के समाधान के लिए बनाया गया था।
(D) जी-20 की अध्यक्षता स्थाई रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के पास है।

27. निम्नलिखित क्षेत्रीय संगठनों को उनकी स्थापना के कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए:
1. ओपेक (OPEC)
2. आसियान (ASEAN)
3. सार्क (SAARC)
4. ओएएस (OAS)
(A) 4, 1, 2, 3
(B) 1, 2, 3, 4
(C) 4, 2, 1, 3
(D) 2, 4, 1, 3

28. 'आसियान शैली' (ASEAN Way) समस्या समाधान की एक ऐसी पद्धति को संदर्भित करती है जो किस पर बल देती है:
(A) बाध्यकारी मध्यस्थता और कानूनी समाधान।
(B) अहस्तक्षेप, आम सहमति बनाना और परामर्श।
(C) बहुमत से मतदान और निर्णयों का प्रवर्तन।
(D) विवादों को सुलझाने के लिए आर्थिक प्रतिबंधों का उपयोग।

29. अमेरिकी राज्यों के संगठन (OAS) के लिए एक प्रमुख चुनौती रही है:
(A) इसके निर्णय लेने में एशियाई देशों का अत्यधिक प्रतिनिधित्व।
(B) प्रमुख दक्षिण अमेरिकी अर्थव्यवस्थाओं की भागीदारी की कमी।
(C) संगठन के भीतर संयुक्त राज्य अमेरिका का ऐतिहासिक प्रभुत्व।
(D) राजनीतिक और मानवाधिकारों की उपेक्षा करते हुए विशेष रूप से आर्थिक मुद्दों पर इसका ध्यान केंद्रित होना।

NODIA

बीच एक औपचारिक राजनीतिक और प्रशासनिक संघ।

9. निर्भरता सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
(A) यह अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को 'केंद्र' और 'परिधि' से युक्त मानता है।
(B) यह सुझाव देता है कि विकासशील देश विश्व अर्थव्यवस्था से अलग होकर आत्मनिर्भरता और विकास प्राप्त कर सकते हैं।
(C) यह मानता है कि अंतरराष्ट्रीय पूंजीवाद वैश्विक विकास के लिए एक कल्याणकारी शक्ति है।
(D) यह तर्क देता है कि केंद्र की संपत्ति परिधि के शोषण पर निर्भर है।

10. अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था की अवधारणाओं के संबंध में सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए।
सूची I: (अवधारणा)
P. NIEO
Q. दक्षिण-दक्षिण सहयोग
R. WTO
S. निर्भरता सिद्धांत
सूची II: (संबद्ध विचार)
1. मराकेश समझौता
2. राउल प्रेबिश
3. जी-77 (G-77)
4. बांडुंग सम्मेलन
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:
(A) P-3, Q-4, R-1, S-2
(B) P-1, Q-2, R-3, S-4
(C) P-3, Q-1, R-4, S-2
(D) P-4, Q-3, R-2, S-1

11. कौन सा संगठन दक्षिण-दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देने से सबसे निकटता से जुड़ा है?
(A) ग्रुप ऑफ 7 (G-7)
(B) आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD)
(C) उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (NATO)
(D) ग्रुप ऑफ 77 (G-77)

12. अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों द्वारा किसी देश को ऋण के बदले अपने सार्वजनिक उद्यमों का निजीकरण करने और सार्वजनिक व्यय कम करने के लिए विवश किया जाता है। इस स्थिति का विश्लेषण किस परिप्रेक्ष्य से सबसे अच्छी तरह किया जा सकता है?
(A) नव-यथार्थवाद
(B) नव-उपनिवेशवाद
(C) वणिकवाद
(D) रचनावाद

13. किस आयोग की रिपोर्टों के प्रकाशन के बाद उत्तर-दक्षिण संवाद को महत्वपूर्ण गति मिली?
(A) ब्रुंडलैंड आयोग
(B) पीयरसन आयोग
(C) ब्रांट आयोग
(D) पाल्मे आयोग

14. विश्व व्यापार संगठन (WTO) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. इसकी स्थापना 'टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौते' (GATT) के उत्तराधिकारी के रूप में की गई थी।
2. डब्ल्यूटीओ में सभी निर्णय बहुमत के मतदान से लिए जाते हैं।
3. 'सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र' (MFN) का सिद्धांत इसके कामकाज का केंद्र है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3

15. निर्भरता सिद्धांत के संदर्भ में 'केंद्र' शब्द क्या दर्शाता है?
(A) विकसित, औद्योगिक और पूंजीवादी राष्ट्र।
(B) गुटनिरपेक्ष देशों का समूह।
(C) विकासशील और अल्पविकसित राष्ट्र।
(D) संयुक्त राष्ट्र का प्रशासनिक मुख्यालय।

16. 1967 में बैंकॉक घोषणा द्वारा किस क्षेत्रीय संगठन की स्थापना की गई थी?
(A) सार्क (SAARC)
(B) आसियान (ASEAN)
(C) ओपेक (OPEC)
(D) ओएएस (OAS)

17. ओपेक (OPEC) के संबंध में नीचे दो कथन दिए गए हैं।
कथन I: ओपेक की स्थापना इसके सदस्य देशों की पेट्रोलियम नीतियों को समन्वित और एकीकृत करने के लिए की गई थी।
कथन II: 1970 के दशक के तेल संकट के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था पर ओपेक का प्रभाव काफी कम हो गया।
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
(D) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।

18. दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
(A) काठमांडू, नेपाल
(B) नई दिल्ली, भारत
(C) कोलंबो, श्रीलंका
(D) ढाका, बांग्लादेश

19. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में लेबल किया गया है।

Downloaded from www.pdf.tube

40. संयुक्त राष्ट्र चार्टर संशोधन की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण बाधा क्या है?
(A) महासभा में साधारण बहुमत के मतदान की आवश्यकता।
(B) संशोधन प्रस्तावित करने के लिए स्पष्ट प्रक्रिया का अभाव।
(C) संशोधन को दो-तिहाई सदस्यों द्वारा अनुसमर्थित किए जाने की आवश्यकता, जिसमें सुरक्षा परिषद के सभी पांच स्थाई सदस्य शामिल हों।
(D) किसी भी परिवर्तन के लिए महासचिव का विरोध।

41. संयुक्त राष्ट्र के संबंध में नीचे दो कथन दिए गए हैं।
कथन I: संयुक्त राष्ट्र के शांति और विकास के दृष्टिकोण को अक्सर एक-दूसरे से जुड़े हुए देखा जाता है।
कथन II: बुतरोस बुतरोस-घाली द्वारा प्रस्तावित संयुक्त राष्ट्र के 'एजेंडा फॉर पीस' में विकास की अनदेखी करते हुए विशेष रूप से सैन्य हस्तक्षेप पर ध्यान केंद्रित किया गया था।
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
(D) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।

42. "शांति के लिए एकता" (Uniting for Peace) प्रस्ताव किस संयुक्त राष्ट्र अंग को अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के मामलों को हाथ में लेने की अनुमति देता है यदि सुरक्षा परिषद में गतिरोध हो?
(A) आर्थिक और सामाजिक परिषद
(B) महासचिव
(C) अंतरराष्ट्रीय न्यायालय
(D) महासभा

43. निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख अंग नहीं है?
(A) सुरक्षा परिषद
(B) अंतरराष्ट्रीय न्यायालय
(C) विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)
(D) सचिवालय

44. संयुक्त राष्ट्र संघ के कामकाज के मूल्यांकन में अक्सर "लोकतांत्रिक घाटे" की ओर संकेत किया जाता है। यह आलोचना मुख्य रूप से किस पर लक्षित है?
(A) महासभा में 'एक देश, एक वोट' का सिद्धांत।
(B) महासचिव की नियुक्ति प्रक्रिया।
(C) आर्थिक और सामाजिक परिषद (ECOSOC) की कार्यवाही में पारदर्शिता का अभाव।
(D) सुरक्षा परिषद के भीतर अलोकतांत्रिक प्रकृति और वीटो शक्ति।

45. निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना अभियानों के वित्तपोषण का सबसे अच्छा वर्णन करता है?
(A) उन्हें सभी सदस्य देशों पर अनिवार्य अंशदान के माध्यम से वित्तपोषित किया जाता है, जिसमें सुरक्षा परिषद के स्थाई सदस्य अधिक हिस्सा देते हैं।
(B) उन्हें केवल स्वैच्छिक योगदान के माध्यम से वित्तपोषित किया जाता है।
(C) उन्हें उस देश द्वारा वित्तपोषित किया जाता है जहाँ अभियान चल रहा है।
(D) उन्हें विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) द्वारा उत्पन्न लाभ से वित्तपोषित किया जाता है।

46. भारतीय विदेश नीति की वह विशिष्ट विशेषता जो अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर स्वतंत्र निर्णय लेने पर बल देती है, किस रूप में जानी जाती है?
(A) पंचशील
(B) गुटनिरपेक्षता (Non-Alignment)
(C) पूर्व की ओर देखो नीति (Look East Policy)
(D) गुजराल सिद्धांत

47. अंतरराष्ट्रीय मामलों में भारत की 'मध्यस्थ भूमिका' कहाँ प्रमुखता से दिखाई दी थी?
(A) वियतनाम युद्ध
(B) फ़ॉकलैंड युद्ध
(C) खाड़ी युद्ध (1991)
(D) कोरियाई युद्ध

48. भारतीय विदेश नीति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह पंचशील, या शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के पांच सिद्धांतों द्वारा निर्देशित है।
2. यह स्वतंत्रता के बाद से निरंतर प्रमुख शक्ति गुटों में से एक के साथ जुड़ी रही है।
3. एक प्रमुख उद्देश्य बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को बढ़ावा देना है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3

49. अपने किस पड़ोसी देश के साथ भारत के संबंधों को अक्सर उसकी 'पड़ोसी पहले' नीति की आधारशिला के रूप में वर्णित किया जाता है?
(A) चीन
(B) पाकिस्तान
(C) भूटान
(D) म्यांमार

50. भारतीय कूटनीति की एक विशेषता "गुजराल सिद्धांत" मुख्य रूप से भारत के किसके साथ संबंधों से संबंधित है?
(A) संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस
(B) छोटे, निकटवर्ती पड़ोसी देश
(C) यूरोपीय संघ
(D) अफ्रीकी राष्ट्र

NODIA

142. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में "वीटो शक्ति" को औपचारिक रूप से किस नियम के रूप में जाना जाता है?
(A) "महाशक्ति एकमतता" (Great power unanimity)
(B) "संप्रभु समानता"
(C) "लोकतांत्रिक बहुमत"
(D) "शांतिपूर्ण समाधान"

143. संयुक्त राष्ट्र महासभा के संबंध में नीचे दो कथन दिए गए हैं।
कथन I: संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव सभी सदस्य देशों पर उसी प्रकार कानूनी रूप से बाध्यकारी होते हैं जैसे सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव।
कथन II: महासभा अंतरराष्ट्रीय मुद्दों के पूर्ण स्पेक्ट्रम पर बहुपक्षीय चर्चा के लिए एक अनूठा मंच प्रदान करती है।
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
(D) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।

144. 'शांति और विकास' के परिप्रेक्ष्य से संयुक्त राष्ट्र संघ के कामकाज का मूल्यांकन करने से पता चलता है कि:
(A) इन दोनों को पूरी तरह से पृथक मुद्दों के रूप में माना जाता है।
(B) एक क्षेत्र में सफलता स्वतः ही दूसरे क्षेत्र में सफलता का आश्वासन देती है।
(C) आर्थिक अभाव और संघर्ष के बीच एक मान्यता प्राप्त संबंध है।
(D) विकास कार्यक्रमों का प्रबंधन पूरी तरह से सुरक्षा परिषद द्वारा किया जाता है।

145. "शांति स्थापना" (peacekeeping), "शांति निर्माण" (peacemaking), और "शांति सुदृढ़ीकरण" (peacebuilding) अवधारणाएं किस महत्वपूर्ण संयुक्त राष्ट्र दस्तावेज में विस्तृत हैं?
(A) मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा
(B) एन एजेंडा फॉर पीस (An Agenda for Peace)
(C) संयुक्त राष्ट्र चार्टर
(D) अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की नियमावली

146. संयुक्त राष्ट्र के वित्तपोषण के लिए एक प्रमुख चुनौती संयुक्त राष्ट्र के संचालन, विशेष रूप से शांति स्थापना की बढ़ती मांग और किसके बीच विसंगति है:
(A) उन्हें पर्याप्त रूप से वित्तपोषित करने के लिए सदस्य देशों की इच्छा।
(B) योग्य कर्मचारी खोजने की संयुक्त राष्ट्र की क्षमता।
(C) विश्व में संघर्षों की संख्या।
(D) संयुक्त राष्ट्र की स्थाई सेना की उपलब्धता।

147. पंचशील समझौते का एक मूल सिद्धांत, और भारतीय विदेश नीति की एक विशेषता है:
(A) पारस्परिक आक्रामकता।
(B) पारस्परिक अहस्तक्षेप।
(C) एक-दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप।
(D) सैन्य गठबंधन का गठन।

148. परमाणु अप्रसार संधि (NPT) पर हस्ताक्षर न करने का भारत का निर्णय उसके इस विचार पर आधारित है कि यह संधि:
(A) परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग पर बहुत अधिक प्रतिबंधात्मक है।
(B) प्रसार को रोकने में प्रभावी नहीं है।
(C) संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन है।
(D) भेदभावपूर्ण है, जो परमाणु "संपन्न" और "विहीन" वर्ग बनाती है।

149. 1990 के दशक की शुरुआत में भारत द्वारा 'लुक ईस्ट पॉलिसी' किस प्राथमिक उद्देश्य के साथ प्रारंभ की गई थी?
(A) सोवियत संघ के प्रभाव का मुकाबला करना।
(B) अपनी कूटनीति को विशेष रूप से बांग्लादेश जैसे अपने पूर्वी पड़ोसियों पर केंद्रित करना।
(C) चीन के विरुद्ध सुरक्षा गठबंधन बनाना।
(D) दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को सुदृढ़ करना।

150. भारतीय विदेश नीति के संबंध में सूची I को सूची II के साथ सुमेलित कीजिए।
सूची I: (नीति/समझौता)
P. पंचशील
Q. गुजराल सिद्धांत
R. लुक ईस्ट पॉलिसी
S. शिमला समझौता
सूची II: (संबद्ध संदर्भ/नेता)
1. पी.वी. नरसिम्हा राव
2. आई.के. गुजराल
3. जवाहरलाल नेहरू
4. इंदिरा गांधी
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:
(A) P-3, Q-2, R-1, S-4
(B) P-1, Q-2, R-3, S-4
(C) P-3, Q-1, R-4, S-2
(D) P-4, Q-3, R-1, S-2

151. कौन सा कथन विदेश नीति में कूटनीति (diplomacy) की भूमिका को सबसे अच्छी तरह परिभाषित करता है?
(A) यह किसी देश के राष्ट्रीय हितों को तैयार करने की प्रक्रिया है।
(B) यह बातचीत, प्रतिनिधित्व और संचार के माध्यम से विदेश नीति का कार्यान्वयन है।
(C) यह विदेश नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए गुप्त अभियानों का उपयोग है।
(D) यह सैन्य शक्ति के उपयोग का पर्यायवाची है।

Click Here to Buy book on Amazon

(A) राज्य और समाज
(B) धन और शक्ति
(C) लोकतंत्र और अधिनायकवाद
(D) धर्म और राजनीति

64. निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए:
1. विश्व व्यापार संगठन (WTO) की स्थापना
2. पहला अंकटाड (UNCTAD) सम्मेलन
3. ब्रांट आयोग की रिपोर्ट "नॉर्थ-साउथ: ए प्रोग्राम फॉर सर्वाइवल" का प्रकाशन
4. जी-77 (G-77) का गठन
(A) 2, 4, 3, 1
(B) 1, 2, 4, 3
(C) 4, 3, 1, 2
(D) 2, 1, 4, 3

65. नव-उपनिवेशवाद का एक मूल सिद्धांत निम्नलिखित में से किस माध्यम से औपनिवेशिक शोषण को जारी रखना है?
(A) प्रत्यक्ष सैन्य शासन।
(B) औपचारिक राजनीतिक विलय।
(C) आर्थिक निर्भरता और सांस्कृतिक साम्राज्यवाद।
(D) पूर्ण और बिना शर्त संप्रभुता प्रदान करना।

66. गेट (GATT) वार्ता के किस दौर के परिणामस्वरूप विश्व व्यापार संगठन (WTO) का निर्माण हुआ?
(A) केनेडी दौर
(B) टोक्यो दौर
(C) उरुग्वे दौर
(D) दोहा दौर

67. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में लेबल किया गया है।
अभिकथन (A): दक्षिण-दक्षिण सहयोग की परिकल्पना एकजुटता पर आधारित बराबरी की साझेदारी के रूप में की गई है।
कारण (R): इसका उद्देश्य उत्तर-दक्षिण सहयोग के पूरक होने के स्थान पर उसे प्रतिस्थापित करना है।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

68. एक 'परिधि' द्वारा 'केंद्र' को सस्ते श्रम और कच्चे माल की आपूर्ति करने का विचार किस सिद्धांत का केंद्र है?
(A) निर्भरता
(B) यथार्थवाद
(C) उदारवाद
(D) रचनावाद

69. उत्तर-दक्षिण संवाद बड़े पैमाने पर किन मुद्दों पर केंद्रित है?
(A) सैन्य और रणनीतिक संतुलन।
(B) विकास, व्यापार और सहायता।
(C) सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान-प्रदान।
(D) सीमा विवाद और क्षेत्रीय दावे।

70. सूची I को सूची II के साथ सुमेलित कीजिए।
सूची I: (संगठन/समूह)
P. ओपेक (OPEC)
Q. जी-20 (G-20)
R. सार्क (SAARC)
S. आसियान (ASEAN)
सूची II: (प्रमुख विशेषता/घटना)
1. दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (SAFTA)
2. बैंकॉक घोषणा
3. 2008 के वित्तीय संकट के बाद से नेताओं का शिखर सम्मेलन
4. 1973 का तेल प्रतिबंध
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:
(A) P-4, Q-3, R-1, S-2
(B) P-3, Q-4, R-2, S-1
(C) P-4, Q-2, R-1, S-3
(D) P-1, Q-3, R-4, S-2

71. निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, न कि प्रमुख अंग?
(A) सुरक्षा परिषद
(B) यूनेस्को (UNESCO)
(C) आर्थिक और सामाजिक परिषद (ECOSOC)
(D) अंतरराष्ट्रीय न्यायालय

72. संयुक्त राष्ट्र के संदर्भ में 'वीटो शक्ति' (निषेधाधिकार) शब्द का तात्पर्य सुरक्षा परिषद के स्थाई सदस्य की किस क्षमता से है?
(A) एक नया प्रस्ताव पेश करना।
(B) किसी मूल प्रस्ताव को अपनाने से रोकना।
(C) परिणाम को प्रभावित किए बिना मतदान से दूर रहना।
(D) अकेले ही महासचिव का चुनाव करना।

73. संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. शांति सैनिकों को अक्सर 'ब्लू हेलमेट' कहा जाता है।
2. ये अभियान मेजबान देश की सहमति पर आधारित होते हैं।
3. शांति सैनिकों द्वारा बल का प्रयोग आत्मरक्षा और शासनादेश की रक्षा तक सीमित है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3

Downloaded from www.pdf.tube

अपने परिवर्तनकारी लक्ष्यों को प्राप्त करने में काफी हद तक विफल रही।
कारण (R): उत्तर के विकसित देशों ने सुदृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति दिखाई और दक्षिण की सभी मांगों पर सहजता से सहमत हो गए।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

121. "दोहा विकास दौर" किस संगठन के तत्वावधान में होने वाली वार्ताओं से जुड़ा है?
(A) अंकटाड (UNCTAD)
(B) डब्ल्यूटीओ (WTO)
(C) अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF)
(D) विश्व बैंक

122. 'बैम्बू कर्टेन' (बांस का पर्दा) के स्थान पर आर्थिक संबंधों के 'बैम्बू नेटवर्क' की अवधारणा किस संगठन के विकास के लिए प्रासंगिक है?
(A) सार्क (SAARC)
(B) आसियान (ASEAN)
(C) ओपेक (OPEC)
(D) जी-20 (G-20)

123. निम्नलिखित में से कौन जी-20 (G-20) का सदस्य नहीं है?
(A) भारत
(B) स्विट्जरलैंड
(C) ब्राजील
(D) दक्षिण अफ्रीका

124. क्षेत्रीय संगठनों के संबंध में सूची I को सूची II के साथ सुमेलित कीजिए।
सूची I: (क्षेत्रीय संगठन)
P. ओएएस (OAS)
Q. ओपेक (OPEC)
R. आसियान (ASEAN)
S. सार्क (SAARC)
सूची II: (स्थापना का वर्ष)
1. 1967
2. 1985
3. 1948
4. 1960
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:
(A) P-3, Q-4, R-1, S-2
(B) P-1, Q-2, R-3, S-4
(C) P-4, Q-3, R-2, S-1
(D) P-3, Q-1, R-4, S-2

125. संयुक्त राष्ट्र के एक प्रमुख अंग न्यास परिषद (Trusteeship Council) ने अपना कार्य क्यों बंद कर दिया?
(A) महासभा द्वारा इसके बजट में कटौती की गई थी।
(B) इसने न्यास क्षेत्रों के स्वतंत्रता की ओर संक्रमण की देखरेख के अपने शासनादेश को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया था।
(C) सुरक्षा परिषद ने इसे भंग करने के लिए मतदान किया।
(D) इसे एक नई संयुक्त राष्ट्र एजेंसी द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था।

126. संयुक्त राष्ट्र के "शांति और विकास के परिप्रेक्ष्य" किस समकालीन वैश्विक ढांचे में परिलक्षित होते हैं?
(A) सहस्राब्दी विकास लक्ष्य (MDGs) और सतत विकास लक्ष्य (SDGs)।
(B) वारसॉ संधि।
(C) ब्रेटन वुड्स प्रणाली।
(D) उत्तर अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौता (NAFTA)।

127. निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र चार्टर संशोधन बहसों में विवाद का एक प्रमुख बिंदु है?
(A) संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय का स्थान।
(B) संयुक्त राष्ट्र में उपयोग की जाने वाली आधिकारिक भाषाएं।
(C) सदस्य देशों के वित्तीय योगदान की गणना का सूत्र।
(D) सुरक्षा परिषद की संरचना और शक्तियां।

128. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थाई सीट के लिए भारत का दावा अक्सर किन अन्य देशों के साथ गठबंधन में किया जाता है, जिन्हें सामूहिक रूप से जी4 (G4) के रूप में जाना जाता है?
(A) चीन, रूस, यूके और फ्रांस
(B) ब्राजील, जर्मनी और जापान
(C) दक्षिण अफ्रीका, नाइजीरिया और मिस्र
(D) पाकिस्तान, इटली और अर्जेंटीना

129. गुजराल सिद्धांत के संबंध में नीचे दो कथन दिए गए हैं।
कथन I: गुजराल सिद्धांत ने प्रस्ताव दिया कि भारत को, दक्षिण एशिया के सबसे बड़े देश के रूप में, छोटे पड़ोसियों से पारस्परिकता नहीं मांगनी चाहिए।
कथन II: यह सिद्धांत चीन और पाकिस्तान सहित भारत के सभी पड़ोसियों पर सार्वभौमिक रूप से लागू किया गया था।
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
(D) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।

130. "रणनीतिक स्वायत्तता" पर बल समकालीन भारतीय विदेश नीति की एक प्रमुख विशेषता है, जिसका अर्थ है:
(A) भारत को वैश्विक मामलों से पृथक करना।
(B) गठबंधनों से बंधे बिना राष्ट्रीय हित के आधार पर विदेश नीति के निर्णय लेना।
(C) सभी अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ

NODIA

87. भारत से जुड़ा एक प्रमुख सुरक्षा समझौता जो क्षेत्रीय स्थिरता के बारे में इसकी चिंताओं को दर्शाता है, वह है:
(A) नाटो (NATO)
(B) वारसॉ संधि
(C) 1971 की भारत-सोवियत शांति, मित्रता और सहयोग संधि
(D) सीटो (SEATO)

88. "भारतीय विदेश नीति की विशिष्ट विशेषताओं" के वाक्यांश में निम्नलिखित में से किसे छोड़कर सभी शामिल होंगे:
(A) सैन्य गठबंधनों की प्रणाली के प्रति प्रतिबद्धता।
(B) एक न्यायपूर्ण और न्यायसंगत अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की वकालत।
(C) अन्य देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का सिद्धांत।
(D) रणनीतिक स्वायत्तता पर ध्यान केंद्रित करना।

89. अपने पड़ोसियों के साथ भारत के संबंध मुख्य रूप से एक नीतिगत ढांचे द्वारा निर्देशित होते हैं जिसे अक्सर कहा जाता है:
(A) मुनरो सिद्धांत
(B) ब्रेझनेव सिद्धांत
(C) पड़ोसी पहले नीति (Neighbourhood First Policy)
(D) खुले द्वार की नीति (Open Door Policy)

90. भारतीय विदेश नीति से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए:
1. पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर
2. भारत का पहला परमाणु परीक्षण (पोखरण-I)
3. 'लुक ईस्ट पॉलिसी' का शुभारंभ
4. शिमला समझौता
(A) 1, 4, 2, 3
(B) 1, 2, 4, 3
(C) 2, 1, 4, 3
(D) 4, 1, 2, 3

91. "ट्रैक-टू कूटनीति" (track-two diplomacy) की अवधारणा में शामिल है:
(A) राष्ट्राध्यक्षों के बीच सीधे की गई बातचीत।
(B) विदेश मंत्रालयों के बीच औपचारिक संचार।
(C) शिक्षाविदों और सेवानिवृत्त अधिकारियों जैसे गैर-सरकारी अभिनेताओं के बीच अनौपचारिक संवाद।
(D) राजनयिक वार्ता का समर्थन करने के लिए सैन्य खतरों का उपयोग।

92. शिमला समझौता एक राजनयिक परिणाम था जो भारत-पाकिस्तान संबंधों में किस प्रमुख घटना के बाद हुआ था?
(A) 1965 का युद्ध
(B) 1971 का युद्ध और बांग्लादेश का निर्माण
(C) कारगिल संघर्ष
(D) 1947-48 का युद्ध

93. भारत के विदेश नीति लक्ष्यों के संबंध में नीचे दो कथन दिए गए हैं।
कथन I: भारत ने सदैव संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थाई सीट की मांग की है।
कथन II: भारत का दावा उसकी विशाल जनसंख्या, लोकतांत्रिक व्यवस्था, आर्थिक विकास और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना में योगदान पर आधारित है।
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
(D) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।

94. निर्भरता सिद्धांत में 'परिधि' (periphery) शब्द उन देशों को संदर्भित करता है जो:
(A) भौगोलिक रूप से अलग-थलग हैं।
(B) आर्थिक रूप से प्रभावशाली और औद्योगिक हैं।
(C) विश्व अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक रूप से वंचित और शोषित हैं।
(D) राजनीतिक रूप से गुटनिरपेक्ष हैं।

95. सूची I को सूची II के साथ सुमेलित कीजिए।
सूची I: (सिद्धांत/अवधारणा)
P. नव-उपनिवेशवाद
Q. उत्तर-दक्षिण संवाद
R. दक्षिण-दक्षिण सहयोग
S. WTO सिद्धांत
सूची II: (संबद्ध शब्द/व्यक्ति)
1. ब्रांट रिपोर्ट
2. सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र (MFN)
3. क्वामे न्क्रूमा
4. बांडुंग की भावना
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:
(A) P-1, Q-3, R-2, S-4
(B) P-3, Q-1, R-4, S-2
(C) P-3, Q-4, R-1, S-2
(D) P-2, Q-1, R-4, S-3

96. डब्ल्यूटीओ (WTO) वार्ता में "सिंगल अंडरटेकिंग" सिद्धांत का अर्थ है कि:
(A) प्रत्येक देश यह चुन सकता है कि वह किन समझौतों का हिस्सा बनना चाहता है।
(B) सब कुछ एक ही पैकेज का हिस्सा है और जब तक सब कुछ तय नहीं हो जाता तब तक कुछ भी तय नहीं माना जाता।
(C) वार्ता प्रत्येक देश के एक ही वार्ताकार द्वारा की जाती है।
(D) वार्ता के प्रत्येक दौर में केवल एक ही विषय पर चर्चा की जा सकती है।

97. जी-77 (G-77), जो उत्तर-दक्षिण संवाद में एक प्रमुख अभिनेता है, किसका गठबंधन है?
(A) 77 सबसे धनी राष्ट्रों का।

Click Here to Buy book on Amazon

51. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में लेबल किया गया है।
अभिकथन (A): भारत ऐतिहासिक रूप से वैश्विक परमाणु निशस्त्रीकरण का प्रबल समर्थक रहा है।
कारण (R): भारत ने परमाणु अप्रसार संधि (NPT) पर हस्ताक्षर के लिए खुलते ही हस्ताक्षर कर दिए थे।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

52. भारत के लिए उसके निकटतम पड़ोस में निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण सुरक्षा चिंता है?
(A) पश्चिम एशिया में राजनीतिक अस्थिरता।
(B) सीमा पार आतंकवाद।
(C) यूरोपीय संघ का विस्तार।
(D) ब्राजील की घरेलू नीतियां।

53. भारतीय विदेश नीति का आधार स्तंभ 'पंचशील' समझौता भारत और किस अन्य देश के बीच हस्ताक्षरित किया गया था?
(A) पाकिस्तान
(B) सोवियत संघ
(C) चीन
(D) नेपाल

54. भारतीय विदेश नीति के संदर्भ में 'कूटनीति' (diplomacy) शब्द का अर्थ है:
(A) बातचीत और संवाद के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय संबंधों का संचालन।
(B) संसद द्वारा विदेश नीति के लक्ष्यों का निर्धारण।
(C) राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करने के लिए सैन्य शक्ति का उपयोग।
(D) अंतरराष्ट्रीय संधियों का घरेलू कार्यान्वयन।

55. निम्नलिखित में से कौन भारतीय विदेश नीति की विशिष्ट विशेषता नहीं है?
(A) विवादों के शांतिपूर्ण समाधान में विश्वास।
(B) उपनिवेशवाद-विरोध और नस्लवाद-विरोध।
(C) सुरक्षा के प्राथमिक साधन के रूप में सैन्य गठबंधनों का अनुसरण।
(D) संयुक्त राष्ट्र के लिए समर्थन।

56. भारत की 'पूर्व की ओर देखो नीति' (Look East Policy), जिसे बाद में 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' में बदल दिया गया, का उद्देश्य किस क्षेत्र के साथ संबंधों को मजबूत करना है?
(A) मध्य एशिया
(B) पश्चिम एशिया
(C) दक्षिण-पूर्व और पूर्व एशिया
(D) अफ्रीका

57. ताशकंद समझौता (1966) और शिमला समझौता (1972) भारत के किसके उदाहरण हैं?
(A) पाकिस्तान के साथ सैन्य समझौता करने के प्रयास।
(B) पाकिस्तान के साथ संघर्षों को सुलझाने के कूटनीतिक प्रयास।
(C) सोवियत संघ के साथ आर्थिक सहयोग समझौते।
(D) इसके परमाणु कार्यक्रम से संबंधित समझौते।

58. भारतीय कूटनीति के संबंध में नीचे दो कथन दिए गए हैं।
कथन I: भारतीय कूटनीति की एक प्रमुख विशेषता इसकी 'मृदु शक्ति' (soft power) पर बल देना है, जिसमें इसके सांस्कृतिक और लोकतांत्रिक मूल्य शामिल हैं।
कथन II: भारत की विदेश नीति 1947 से पूरी तरह से स्थिर और अपरिवर्तित रही है।
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
(D) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।

59. 'गुजराल सिद्धांत' का मूल सिद्धांत यह है कि भारत को:
(A) सभी पड़ोसियों के साथ अपने व्यवहार में सख्त पारस्परिकता की अपेक्षा करनी चाहिए।
(B) छोटे पड़ोसियों को सद्भावना के साथ एकतरफा रियायतें देनी चाहिए।
(C) अपने बड़े पड़ोसियों का मुकाबला करने के लिए सैन्य गठबंधन बनाना चाहिए।
(D) राजनीतिक संबंधों के स्थान पर आर्थिक संबंधों को प्राथमिकता देनी चाहिए।

NODIA

60. चीन के प्रति भारत की लंबे समय से चली आ रही सुरक्षा चिंताएं मुख्य रूप से किसके इर्द-गिर्द घूमती हैं?
(A) धार्मिक और सांस्कृतिक विवाद।
(B) अनसुलझे सीमा और क्षेत्रीय मुद्दे।
(C) लैटिन अमेरिका में प्रभाव के लिए प्रतिस्पर्धा।
(D) डब्ल्यूटीओ (WTO) नीतियों पर असहमति।

61. निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है?
(A) निर्भरता सिद्धांत - केंद्र-परिधि संबंध
(B) दक्षिण-दक्षिण सहयोग - जी-77 (G-77)
(C) NIEO - ब्रेटन वुड्स संस्थान
(D) WTO - दोहा दौर

62. नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की मांग सबसे प्रभावशाली ढंग से किसके द्वारा व्यक्त की गई थी?
(A) जी-7 (G-7) देशों द्वारा।
(B) गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) और जी-77 (G-77) द्वारा।
(C) वारसॉ संधि देशों द्वारा।
(D) ओईसीडी (OECD) द्वारा।

63. अंतरराष्ट्रीय संबंधों की राजनीतिक अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किसके बीच संबंधों की जांच करती है?

(C) सुरक्षा परिषद को सैन्य बल सहित प्रवर्तन कार्रवाई करने के लिए अधिकृत करता है।
(D) अंतरराष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों को स्थापित करता है।

109. निम्नलिखित में से कौन 'संयुक्त राष्ट्र संघ के भीतर शक्ति संघर्ष और कूटनीति' की अवधारणा को सबसे अच्छी तरह समझाता है?
(A) प्रभाव के लिए संयुक्त राष्ट्र और क्षेत्रीय संगठनों के बीच चल रही प्रतिस्पर्धा।
(B) राज्यों द्वारा गठबंधनों के माध्यम से राष्ट्रीय लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र मंच का उपयोग।
(C) विभिन्न प्रशासनिक विभागों के बीच आंतरिक नौकरशाही राजनीति।
(D) आईसीजे और सुरक्षा परिषद के सदस्यों से जुड़े औपचारिक कानूनी विवाद।

110. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार का एक प्रस्ताव, जिसमें वीटो शक्ति के बिना स्थाई सदस्यों की एक नई श्रेणी बनाना शामिल है, अक्सर किस समूह द्वारा समर्थित योजना के रूप में संदर्भित किया जाता है?
(A) P5 देश
(B) G4 राष्ट्र (ब्राजील, जर्मनी, भारत, जापान)
(C) अफ्रीकी संघ
(D) 'आम सहमति के लिए एकता' समूह

111. संयुक्त राष्ट्र का मुख्य बजट किस अंग द्वारा अनुमोदित किया जाता है?
(A) सुरक्षा परिषद
(B) महासचिव
(C) महासभा
(D) आर्थिक और सामाजिक परिषद

112. संयुक्त राष्ट्र के संदर्भ में "P5" शब्द का तात्पर्य है:
(A) पांच सबसे अधिक आबादी वाले देश।
(B) संयुक्त राष्ट्र बजट में पांच सबसे बड़े वित्तीय योगदानकर्ता।
(C) सुरक्षा परिषद के पांच स्थाई सदस्य।
(D) संयुक्त राष्ट्र चार्टर के पांच मूल हस्ताक्षरकर्ता।

113. भारत की विदेश नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) का संस्थापक सदस्य था।
2. 'गुजराल सिद्धांत' छोटे पड़ोसियों के साथ सख्त पारस्परिकता की नीति की वकालत करता है।
3. 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी', 'लुक ईस्ट पॉलिसी' की उत्तराधिकारी है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3

114. 1955 का 'बांडुंग सम्मेलन' किसके गठन का एक महत्वपूर्ण अग्रदूत था?
(A) संयुक्त राष्ट्र
(B) गुटनिरपेक्ष आंदोलन
(C) वारसॉ संधि
(D) यूरोपीय आर्थिक समुदाय

115. भारतीय कूटनीति की एक विशिष्ट विशेषता किसके लिए इसका निरंतर समर्थन रही है?
(A) उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद।
(B) अंतरराष्ट्रीय मामलों में एकपक्षवाद (unilateralism)।
(C) वैश्विक निशस्त्रीकरण और शस्त्र नियंत्रण।
(D) विरोधी सैन्य गुटों का गठन।

116. भारत की सुरक्षा चिंताएं बहुआयामी हैं और इसमें निम्नलिखित को छोड़कर सभी शामिल हैं:
(A) हिंद महासागर में समुद्री सुरक्षा।
(B) अंटार्कटिका में राजनीतिक स्थिति।
(C) सीमा पार घुसपैठ और आतंकवाद।
(D) चीन के साथ क्षेत्रीय रणनीतिक संतुलन।

117. 1971 में भारत द्वारा एक प्रमुख शक्ति के साथ हस्ताक्षरित किस समझौते का बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के दौरान उसकी सुरक्षा गणनाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा?
(A) पाकिस्तान के साथ शिमला समझौता।
(B) चीन के साथ पंचशील समझौता।
(C) सोवियत संघ (USSR) के साथ शांति, मित्रता और सहयोग की संधि।
(D) अमेरिका के साथ रक्षा सहयोग समझौता।

118. अपनी मध्यस्थ भूमिका में, भारत अक्सर किस पर बल देता है?
(A) प्रथम विकल्प के रूप में सैन्य हस्तक्षेप।
(B) बाहरी शक्तियों द्वारा तैयार किए गए समाधानों को थोपना।
(C) संवाद, बातचीत और विवादों का शांतिपूर्ण समाधान।
(D) संघर्षरत पक्षों को विवश करने के लिए आर्थिक प्रतिबंधों का उपयोग।

119. 1990 के दशक में भारतीय विदेश नीति में एक प्रमुख परिवर्तन क्या था?
(A) आर्थिक उदारीकरण और पश्चिम के साथ अधिक जुड़ाव की ओर कदम।
(B) गुटनिरपेक्षता का औपचारिक त्याग और सैन्य गुट में शामिल होना।
(C) पश्चिमी देशों में अपने दूतावासों को बंद करना।
(D) अपने निकटतम पड़ोस से पूरी तरह अलग होना।

120. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में लेबल किया गया है।
अभिकथन (A): नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था (NIEO)

Downloaded from www.pdf.tube

(B) विकासशील देशों का।
(C) यूरोपीय राष्ट्रों का।
(D) तेल निर्यातक राष्ट्रों का।

98. अंतरराष्ट्रीय संबंधों की राजनीतिक अर्थव्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. नव-उपनिवेशवाद यह सुझाव देता है कि राजनीतिक स्वतंत्रता कई पूर्व उपनिवेशों के लिए आर्थिक स्वतंत्रता में परिवर्तित नहीं हुई है।
2. डब्ल्यूटीओ अपने सदस्यों के बीच संरक्षणवादी नीतियों और उच्च टैरिफ को बढ़ावा देता है।
3. NIEO का उद्देश्य ब्रेटन वुड्स में स्थापित मौजूदा आर्थिक संरचनाओं को बनाए रखना था।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) केवल 1
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3

99. निर्भरता सिद्धांतकारों का एक केंद्रीय तर्क यह है कि केंद्र देशों में विकास और परिधीय देशों में अल्पविकास:
(A) दो स्वतंत्र और असंबंधित प्रक्रियाएं हैं।
(B) एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जो आंतरिक रूप से जुड़े हुए हैं।
(C) एक अस्थायी चरण है जिसे मुक्त व्यापार के माध्यम से दूर किया जाएगा।
(D) परिधीय राष्ट्रों में सांस्कृतिक कमियों का परिणाम है।

100. "आसियान क्षेत्रीय मंच (ARF)" मुख्य रूप से किससे संबंधित है?
(A) आर्थिक एकीकरण और मुक्त व्यापार।
(B) सांस्कृतिक और सामाजिक आदान-प्रदान कार्यक्रम।
(C) एशिया-प्रशांत में सुरक्षा संवाद और विश्वास-निर्माण।
(D) मौद्रिक नीतियों का समन्वय।

101. किस संगठन के चार्टर में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इसका एक अनिवार्य उद्देश्य "प्रतिनिधि लोकतंत्र को बढ़ावा देना और सुदृढ़ करना" है?
(A) सार्क (SAARC)
(B) ओपेक (OPEC)
(C) आसियान (ASEAN)
(D) ओएएस (OAS)

102. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में लेबल किया गया है।
अभिकथन (A): वैश्विक आर्थिक शासन के लिए जी-20, जी-7/जी-8 की तुलना में अधिक प्रभावशाली निकाय बन गया है।
कारण (R): जी-20 की सदस्यता वैश्विक अर्थव्यवस्था का अधिक प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

103. सार्क (SAARC) की धीमी प्रगति का उत्तरदायित्व अक्सर किसे दिया जाता है?
(A) इसके सदस्यों के बीच सामान्य सांस्कृतिक विरासत का अभाव।
(B) भारत और पाकिस्तान के बीच राजनीतिक तनाव।
(C) सदस्य देशों के बीच भौगोलिक दूरी।
(D) इसकी बैठकों में बाहरी शक्तियों का प्रभुत्व।

104. निम्नलिखित में से कौन सार्क (SAARC) का पर्यवेक्षक है, पूर्ण सदस्य नहीं?
(A) नेपाल
(B) श्रीलंका
(C) चीन
(D) बांग्लादेश

105. ओपेक (OPEC) के गठन की एक मुख्य प्रेरणा क्या थी?
(A) बहुराष्ट्रीय तेल कंपनियों ("सेवन सिस्टर्स") की शक्ति का मुकाबला करना।
(B) मध्य पूर्व में लोकतंत्र को बढ़ावा देना।
(C) तेल उत्पादक देशों के लिए एक सैन्य गठबंधन बनाना।
(D) अक्षय ऊर्जा स्रोतों की ओर वैश्विक बदलाव को प्रोत्साहित करना।

106. अपने सभी सदस्यों की 'संप्रभु समानता' का सिद्धांत किस संगठन की एक मौलिक अवधारणा है?
(A) यूरोपीय संघ
(B) संयुक्त राष्ट्र
(C) जी-20
(D) ओपेक (OPEC)

107. अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) के संबंध में नीचे दो कथन दिए गए हैं।
कथन I: अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) युद्ध अपराधों और नरसंहार के लिए व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकता है।
कथन II: ICJ का प्राथमिक कार्य राज्यों द्वारा इसे सौंपे गए कानूनी विवादों को निपटाना है।
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
(D) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।

108. संयुक्त राष्ट्र चार्टर का "अध्याय VII" महत्वपूर्ण है क्योंकि यह:
(A) नए सदस्यों को प्रवेश देने की प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार करता है।
(B) महासभा के कार्यों का वर्णन करता है।

NODIA

जुड़ना।
(D) आर्थिक विकास के स्थान पर सैन्य विकास को प्राथमिकता देना।

131. 'उत्तर-दक्षिण संवाद' में 'दक्षिण' शब्द का तात्पर्य सामान्यतः किससे है?
(A) दक्षिणी गोलार्ध के देश।
(B) विकासशील और अल्पविकसित देश।
(C) केवल गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य देश।
(D) जी-7 (G-7) देश।

132. एक प्रमुख उपनिवेशवाद विरोधी नेता क्वामे न्क्रूमा, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में किस अवधारणा के प्रबल समर्थक थे?
(A) नव-उपनिवेशवाद (Neo-colonialism)
(B) डोमिनो सिद्धांत
(C) इतिहास का अंत
(D) सभ्यताओं का संघर्ष

133. निर्भरता सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह वैश्विक पूंजीवाद के लाभों के बारे में एक आशावादी सिद्धांत है।
2. यह मानता है कि 'केंद्र' का विकास और 'परिधि' का अल्पविकास आपस में जुड़े हुए हैं।
3. इसकी उत्पत्ति लैटिन अमेरिकी देशों के अनुभवों से हुई है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3

134. निम्नलिखित में से कौन सा डब्ल्यूटीओ (WTO) व्यापार प्रणाली का एक प्रमुख सिद्धांत है?
(A) पूर्व औपनिवेशिक शक्तियों के लिए अधिमान्य व्यवहार।
(B) गैर-भेदभाव का सिद्धांत (MFN और राष्ट्रीय व्यवहार)।
(C) मनमाने ढंग से उच्च टैरिफ निर्धारित करने का प्रत्येक देश का अधिकार।
(D) सभी क्षेत्रों में सरकारी स्वामित्व वाले एकाधिकार को बढ़ावा देना।

135. दक्षिण-दक्षिण सहयोग को अक्सर किसकी अभिव्यक्ति के रूप में वर्णित किया जाता है?
(A) विकासशील देशों के बीच सामूहिक आत्मनिर्भरता।
(B) उभरती अर्थव्यवस्थाओं पर निर्भरता का एक नया रूप।
(C) वैश्विक मामलों में जी-7 (G-7) का प्रभुत्व।
(D) क्षेत्रीय संगठनों की विफलता।

136. निम्नलिखित को उनके होने के कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए:
1. सार्क (SAARC) की स्थापना
2. बैंकॉक घोषणा को अपनाना (आसियान की स्थापना)
3. राष्ट्राध्यक्षों के शिखर सम्मेलन के स्तर पर जी-20 की स्थापना
4. ओपेक (OPEC) का गठन
(A) 4, 2, 1, 3
(B) 2, 4, 1, 3
(C) 4, 1, 2, 3
(D) 1, 2, 4, 3

137. "आसियान शैली" (ASEAN Way) के बारे में कौन सा कथन गलत है?
(A) यह आम सहमति और परामर्श को महत्व देता है।
(B) यह अहस्तक्षेप के सिद्धांत का कड़ाई से पालन करता है।
(C) यह निर्णयों को लागू करने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी संस्थानों पर निर्भर करता है।
(D) यह परिणामोन्मुखी दृष्टिकोण के स्थान पर प्रक्रिया-उन्मुख दृष्टिकोण है।

138. अमेरिकी राज्यों के संगठन (OAS) का मुख्यालय कहाँ है?
(A) वाशिंगटन, डी.सी., यूएसए
(B) ब्रासीलिया, ब्राजील
(C) बोगोटा, कोलंबिया
(D) मैक्सिको सिटी, मैक्सिको

139. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में लेबल किया गया है।
अभिकथन (A): जी-20 (G-20) में यूरोपीय संघ एक सदस्य के रूप में सम्मिलित है।
कारण (R): जी-20 का ध्यान विशेष रूप से राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों पर है, आर्थिक मामलों पर नहीं।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

140. सार्क (SAARC) की सीमित सफलता का एक प्राथमिक कारण है:
(A) इसके सदस्यों के बीच आर्थिक प्रणालियों की विविधता।
(B) एक साझा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का अभाव।
(C) द्विपक्षीय राजनीतिक संघर्षों का व्यापक प्रभाव।
(D) स्थाई सचिवालय की कमी।

141. ओपेक (OPEC) का मुख्य उद्देश्य है:
(A) तेल बाजारों को विनियमित और स्थिर करना।
(B) अक्षय ऊर्जा की ओर वैश्विक संक्रमण को बढ़ावा देना।
(C) अपने सदस्यों के लिए एक सैन्य गठबंधन के रूप में कार्य करना।
(D) गैर-तेल उत्पादक देशों को विकास सहायता प्रदान करना।

Click Here to Buy book on Amazon

74. "आसियान+3" (ASEAN+3) ढांचे में दस आसियान सदस्यों के अतिरिक्त कौन से तीन देश शामिल हैं?
(A) भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड
(B) चीन, जापान, दक्षिण कोरिया
(C) अमेरिका, रूस, भारत
(D) पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका

75. अन्य सदस्य देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का सिद्धांत किस संगठन के दृष्टिकोण की आधारशिला है?
(A) आसियान (ASEAN)
(B) यूरोपीय संघ
(C) डब्ल्यूटीओ (WTO)
(D) अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय

76. जी-20 (G-20) किसका मिश्रण है?
(A) केवल औद्योगिक देशों का।
(B) केवल विकासशील देशों का।
(C) यूरोपीय संघ सहित औद्योगिक और विकासशील देशों दोनों का।
(D) केवल जी-7 और ब्रिक्स (BRICS) देशों का।

77. सार्क (SAARC) की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि किसकी स्थापना रही है?
(A) एक साझा मुद्रा।
(B) एक एकीकृत सैन्य कमान।
(C) दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (SAFTA)।
(D) बाध्यकारी शक्तियों वाला एक क्षेत्रीय न्यायालय।

78. ओपेक (OPEC) के संबंध में नीचे दो कथन दिए गए हैं।
कथन I: ओपेक का मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में स्थित है।
कथन II: ऑस्ट्रिया ओपेक का संस्थापक और वर्तमान सदस्य है।
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
(D) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।

79. निम्नलिखित में से 1948 में स्थापित सबसे पुराना क्षेत्रीय संगठन कौन सा है?
(A) आसियान (ASEAN)
(B) ओएएस (OAS)
(C) सार्क (SAARC)
(D) जी-20 (G-20)

80. विश्व व्यापार संगठन (WTO) के भीतर निर्णय लेने की प्राथमिक पद्धति क्या है?
(A) आम सहमति (Consensus)
(B) साधारण बहुमत मतदान
(C) व्यापार मात्रा के आधार पर भारित मतदान
(D) पांच सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के लिए वीटो शक्ति

81. संयुक्त राष्ट्र संघ के कामकाज के विरुद्ध लगाए गए मुख्य आरोपों में से एक शक्तिशाली राज्यों को एकपक्षीय सैन्य कार्रवाई करने से रोकने में इसकी असमर्थता है। यह इसके किस उद्देश्य को दुर्बल करता है?
(A) आर्थिक विकास को बढ़ावा देना।
(B) अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना।
(C) मानवाधिकारों की रक्षा करना।
(D) सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देना।

82. 'एजेंडा फॉर पीस' रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र के किस पूर्व महासचिव से जुड़ी है?
(A) कोफी अन्नान
(B) बुतरोस बुतरोस-घाली
(C) यू थांट
(D) जेवियर पेरेज़ डी कुएलर

83. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में लेबल किया गया है।
अभिकथन (A): संयुक्त राष्ट्र चार्टर संशोधन की मांगों में अक्सर सुरक्षा परिषद का विस्तार शामिल होता है।
कारण (R): सुरक्षा परिषद की वर्तमान संरचना को 21वीं सदी की भू-राजनीतिक वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करने वाला माना जाता है।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

84. संयुक्त राष्ट्र की संरचना के संदर्भ में, सचिवालय को इसके किस रूप में सबसे अच्छी तरह वर्णित किया गया है?
(A) न्यायिक शाखा
(B) विधायी शाखा
(C) कार्यकारी शाखा
(D) प्रशासनिक शाखा

85. 20वीं सदी के मध्य में नए स्वतंत्र देशों के नेता के रूप में भारत की भूमिका किसकी एक प्रमुख विशेषता थी?
(A) सुरक्षा समझौतों में इसकी सदस्यता।
(B) गुटनिरपेक्ष विदेश नीति।
(C) परमाणु हथियार कार्यक्रम।
(D) आर्थिक उदारीकरण की नीतियां।

86. निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोस के संघर्ष में भारत की मध्यस्थ भूमिका का एक उत्कृष्ट उदाहरण है?
(A) 1979 के अफगानिस्तान पर सोवियत आक्रमण में इसकी भूमिका।
(B) श्रीलंकाई जातीय संघर्ष में इसका हस्तक्षेप जिसके कारण 1987 का भारत-श्रीलंका समझौता हुआ।
(C) 2003 के इराक युद्ध के दौरान इसकी स्थिति।
(D) यूरोपीय संघ के साथ इसकी व्यापार वार्ता।

NODIA

152. अपने पड़ोसियों के साथ भारत के संबंध अक्सर "असममिति" (asymmetry) नामक कारक से जटिल हो जाते हैं, जो संदर्भित करता है:
(A) अधिकांश पड़ोसियों के साथ साझा सीमाओं का अभाव।
(B) भारत और उसके छोटे पड़ोसियों के बीच आकार, अर्थव्यवस्था और सैन्य शक्ति में महत्वपूर्ण अंतर।
(C) क्षेत्र में विभिन्न राजनीतिक प्रणालियां।
(D) राजनयिक संबंधों की अनुपस्थिति।

153. शीत युद्ध काल का एक प्रमुख सुरक्षा समझौता जिसका भारत ने निरंतर विरोध किया था, वह था:
(A) गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM)
(B) दक्षिण पूर्व एशिया संधि संगठन (SEATO)
(C) भारत-सोवियत संधि
(D) संयुक्त राष्ट्र चार्टर

154. प्रौद्योगिकी और पूंजी के लिए 'केंद्र' पर 'परिधि' की निर्भरता किसका एक केंद्रीय विषय है?
(A) नव-यथार्थवादी सिद्धांत
(B) नव-उदारवादी सिद्धांत
(C) निर्भरता सिद्धांत
(D) रचनावादी सिद्धांत

155. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था (NIEO) विकसित देशों द्वारा रखे गए प्रस्तावों का एक समूह था।
2. उत्तर-दक्षिण संवाद उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के देशों के बीच चर्चा को संदर्भित करता है।
3. दक्षिण-दक्षिण सहयोग विकासशील देशों के बीच सहयोग का एक ढांचा है।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) केवल 3
(B) केवल 1 और 2
(C) केवल 2 और 3
(D) 1, 2 और 3

156. निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण-दक्षिण सहयोग का लक्ष्य नहीं है?
(A) सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना।
(B) अंतरराष्ट्रीय मंच पर बातचीत की क्षमता बढ़ाना।
(C) दक्षिणी राज्यों के बीच औपनिवेशिक निर्भरता की एक नई प्रणाली बनाना।
(D) विकास के अनुभव और तकनीकी ज्ञान साझा करना।

157. डब्ल्यूटीओ (WTO) के विवाद निपटान तंत्र को गेट (GATT) प्रणाली की तुलना में एक महत्वपूर्ण सुधार माना जाता है क्योंकि:
(A) इसके फैसले केवल परामर्शदात्री और गैर-बाध्यकारी होते हैं।
(B) यह अधिक सुव्यवस्थित और कानूनी रूप से बाध्यकारी प्रक्रिया की अनुमति देता है।
(C) इसका उपयोग केवल विकसित देशों द्वारा किया जा सकता है।
(D) इसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

158. यह विचार कि पूर्व उपनिवेश अभी भी अपने पूर्व शासकों के आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव के अधीन हैं, क्या कहलाता है?
(A) वि-उपनिवेशीकरण
(B) नव-उपनिवेशवाद
(C) आत्मनिर्णय
(D) वणिकवाद

159. विश्व व्यापार में जी-20 (G-20) की हिस्सेदारी लगभग कितने प्रतिशत है?
(A) 25%
(B) 50%
(C) 75%
(D) 95%

160. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में लेबल किया गया है।
अभिकथन (A): आसियान क्षेत्रीय मंच (ARF) एशिया में सुरक्षा संवाद के लिए प्रमुख मंच है।
कारण (R): ARF आम सहमति और अहस्तक्षेप के सिद्धांतों पर कार्य करता है, जो सभी प्रतिभागियों के लिए सहज गति से आगे बढ़ता है।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

161. सार्क (SAARC) की विफलता का एक प्रमुख बिंदु इसकी किस असमर्थता को माना जाता है?
(A) नियमित वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित करना।
(B) सचिवालय स्थापित करना।
(C) प्रमुख समझौतों पर घोषणात्मक चरण से कार्यान्वयन चरण तक प्रभावी ढंग से आगे बढ़ना।
(D) क्षेत्र के बाहर से पर्यवेक्षकों को आकर्षित करना।

162. निम्नलिखित में से किसको छोड़कर सभी ओपेक (OPEC) के संस्थापक सदस्य हैं?
(A) ईरान
(B) इराक
(C) नाइजीरिया
(D) सऊदी अरब

163. इंटर-अमेरिकन डेमोक्रेटिक चार्टर, जो ओएएस (OAS) को उस सदस्य देश को निलंबित करने की अनुमति देता है जहाँ

(B) सदस्य देशों की रुचि में कमी।
(C) किसी भी संशोधन के लिए P5 की सहमति की आवश्यकता।
(D) संयुक्त राष्ट्र महासचिव का विरोध।

233. "मध्यम शक्ति" (Middle Power) शब्द, जिसका उपयोग अक्सर कनाडा या ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों का वर्णन करने के लिए किया जाता है, किस प्रकार की राजनयिक भूमिका से जुड़ा है जिसे भारत ने भी निभाया है?
(A) आधिपत्यकारी भूमिका
(B) अलगाववादी भूमिका
(C) मध्यस्थ भूमिका (Mediatory role)
(D) साम्राज्यवादी भूमिका

234. गुजराल सिद्धांत के संबंध में नीचे दो कथन दिए गए हैं।
कथन I: गुजराल सिद्धांत का मूल द्विपक्षीय संबंधों में सख्त और तत्काल पारस्परिकता का सिद्धांत है।
कथन II: यह सिद्धांत भारत के छोटे दक्षिण एशियाई पड़ोसियों के साथ संबंधों को प्रबंधित करने के लिए तैयार किया गया था।
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
(D) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।

235. गुटनिरपेक्ष दृष्टिकोण की निरंतरता, भले ही संशोधित रूप में जिसे "रणनीतिक स्वायत्तता" कहा जाता है, किसकी एक विशिष्ट विशेषता है?
(A) अमेरिकी विदेश नीति
(B) चीनी विदेश नीति
(C) भारतीय विदेश नीति
(D) रूसी विदेश नीति

236. 1971 की भारत-सोवियत संधि एक महत्वपूर्ण सुरक्षा समझौता था जिसने:
(A) भारत को वारसॉ संधि का सदस्य बना दिया।
(B) 1971 के बांग्लादेश युद्ध से पूर्व भारत को सुरक्षा आश्वासन प्रदान किया।
(C) मुख्य रूप से एक आर्थिक और व्यापार समझौता था।
(D) कश्मीर मुद्दे के तत्काल समाधान का मार्ग प्रशस्त किया।

237. नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था (NIEO) किसमें सुधार की मांग थी?
(A) संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद।
(B) ब्रेटन वुड्स आर्थिक प्रणाली।
(C) मानवाधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय कानूनी ढांचा।
(D) वैश्विक सुरक्षा संरचना।

238. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. दक्षिण-दक्षिण सहयोग मुख्य रूप से एक राजनीतिक और सैन्य गठबंधन है।
2. जी-77 का गठन विकासशील देशों के सामूहिक आर्थिक हितों को व्यक्त करने के लिए किया गया था।
3. उत्तर-दक्षिण संवाद ने विकसित और विकासशील देशों के बीच सभी आर्थिक विवादों को सफलतापूर्वक सुलझा लिया है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) केवल 2
(B) केवल 1 और 3
(C) केवल 2 और 3
(D) 1, 2 और 3

239. कच्चे माल के निर्यातक के रूप में वैश्विक अर्थव्यवस्था में एकीकृत होने के बावजूद आर्थिक जड़ता का अनुभव करने वाला देश किसके लिए एक केस स्टडी है?
(A) लोकतांत्रिक शांति सिद्धांत
(B) निर्भरता सिद्धांत
(C) शक्ति संतुलन सिद्धांत
(D) खेल सिद्धांत

240. सूची I को सूची II के साथ सुमेलित कीजिए।
सूची I: (संगठन)
P. डब्ल्यूटीओ (WTO)
Q. आसियान (ASEAN)
R. ओएएस (OAS)
S. संयुक्त राष्ट्र संघ
सूची II: (संस्थापक दस्तावेज/घटना)
1. बैंकॉक घोषणा
2. बोगोटा का चार्टर
3. सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन
4. मराकेश समझौता
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:
(A) P-1, Q-4, R-2, S-3
(B) P-4, Q-2, R-1, S-3
(C) P-4, Q-1, R-2, S-3
(D) P-3, Q-1, R-2, S-4

241. आंतरिक मामलों में अहस्तक्षेप का सिद्धांत किस संगठन के लिए अपने सदस्यों के बीच मानवाधिकारों के उल्लंघन से निपटने के दौरान एक बड़ी चुनौती रहा है?
(A) आसियान (ASEAN)
(B) यूरोपीय संघ
(C) जी-20 (G-20)
(D) डब्ल्यूटीओ (WTO)

242. जी-20 (G-20) का मुख्य उद्देश्य है:
(A) वैश्विक सैन्य संकटों का समाधान करना।
(B) अंतरराष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय स्थिरता पर संवाद के लिए एक मंच प्रदान करना।
(C) अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण कानून बनाना।
(D) अपने सदस्यों की विदेश नीतियों का समन्वय करना।

Downloaded from www.pdf.tube

STUDYING FROM PDFs?

THINK AGAIN.

If you are studying only from PDFs,
you are wasting valuable time.

Research shows that learning from

PRINTED BOOKS has up to

4× HIGHER RETENTION

than studying from screens.

PRINT BOOK = BETTER MEMORY

PDF = LOWER RETENTION

Those who study from **PRINTED BOOKS**
move **AHEAD.**

Others are left **BEHIND**
in competition.

In competitive exams,
being average is not enough.

STAY ONE STEP AHEAD.

(D) वैचारिक-राजनीतिक

174. निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण-दक्षिण सहयोग का सबसे अच्छा उदाहरण है?
(A) मार्शल प्लान।
(B) भारत-ब्राजील-दक्षिण अफ्रीका (IBSA) संवाद मंच।
(C) ओईसीडी (OECD) विकास सहायता कार्यक्रम।
(D) आईएमएफ (IMF) से किसी विकासशील देश को ऋण।

175. डब्ल्यूटीओ (WTO) के भीतर 'राष्ट्रीय व्यवहार' के सिद्धांत का अर्थ है कि:
(A) एक देश को अपने घरेलू उत्पादों के साथ आयात की तुलना में बेहतर व्यवहार करना चाहिए।
(B) आयातित वस्तुओं के बाजार में प्रवेश करने के पश्चात, उनके साथ घरेलू रूप से उत्पादित वस्तुओं की तुलना में कम अनुकूल व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए।
(C) सभी विदेशी वस्तुओं के साथ उनके मूल देश की परवाह किए बिना समान व्यवहार किया जाना चाहिए।
(D) एक देश अपनी सीमाओं के भीतर कार्य करने वाली किसी भी विदेशी कंपनी का राष्ट्रीयकरण कर सकता है।

176. किसके प्रभावों के विश्लेषण में अध्ययन के क्षेत्र के रूप में अंतरराष्ट्रीय संबंधों की राजनीतिक अर्थव्यवस्था को प्रमुखता मिली?
(A) नेपोलियन के युद्ध।
(B) वि-उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया।
(C) वैश्वीकरण और आर्थिक अन्योन्याश्रयता का उदय।
(D) वेस्टफेलिया की संधि।

177. एक देश जो विकसित राष्ट्रों को एकल प्राथमिक वस्तु (जैसे, कॉफी या तांबा) के निर्यात पर निर्भर है और निर्मित वस्तुओं का आयात करता है, वह किस सिद्धांत द्वारा वर्णित स्थिति में है?
(A) यथार्थवाद
(B) निर्भरता सिद्धांत
(C) उदारवाद
(D) खेल सिद्धांत

178. निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए:
1. बेलग्रेड में पहला गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन
2. बांडुंग सम्मेलन
3. NIEO की मांग करने वाला अल्जीयर्स शिखर सम्मेलन
4. जी-77 (G-77) की स्थापना
(A) 2, 1, 4, 3
(B) 1, 2, 3, 4
(C) 2, 4, 1, 3
(D) 4, 2, 1, 3

179. आसियान (ASEAN) की एक प्रमुख विशेषता आम सहमति आधारित निर्णय लेने पर इसका ध्यान केंद्रित करना है, जिसे अक्सर कहा जाता है:
(A) आसियान पद्धति
(B) आसियान शैली (ASEAN Way)
(C) आसियान शासनादेश
(D) आसियान सिद्धांत

180. जी-20 (G-20) के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
(A) इसका स्थाई सचिवालय जिनेवा में है।
(B) इसका गठन 1975 में तेल की कीमतों के झटकों से निपटने के लिए किया गया था।
(C) इसकी अध्यक्षता वार्षिक रूप से इसके सदस्यों के बीच बदलती रहती है।
(D) यह एक औपचारिक सैन्य गठबंधन है।

NODIA

181. दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय (South Asian University) किस क्षेत्रीय संगठन की एक पहल है?
(A) आसियान (ASEAN)
(B) जी-20 (G-20)
(C) सार्क (SAARC)
(D) ओएएस (OAS)

182. वैश्विक तेल कीमतों को प्रभावित करने की ओपेक (OPEC) की क्षमता किसकी शक्ति को प्रदर्शित करती है?
(A) एक सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था।
(B) एक उपभोक्ता बहिष्कार।
(C) एक उत्पादक संघ (कार्टेल)।
(D) एक मुक्त बाजार तंत्र।

183. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में लेबल किया गया है।
अभिकथन (A): अमेरिकी राज्यों के संगठन (OAS) को अमेरिकी आधिपत्य की धारणा से संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ा है।
कारण (R): OAS का मुख्यालय वाशिंगटन डी.सी. में स्थित है और अमेरिका इसका सबसे बड़ा वित्तीय योगदानकर्ता है।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

184. संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी?
(A) 1919
(B) 1939
(C) 1945
(D) 1950

लोकतांत्रिक व्यवस्था में असंवैधानिक बाधा उत्पन्न हुई है, किस संगठन के लिए एक प्रमुख उपकरण है?
(A) आसियान (ASEAN)
(B) सार्क (SAARC)
(C) ओएएस (OAS)
(D) जी-20 (G-20)

164. संयुक्त राष्ट्र की संरचना शक्ति संघर्ष और प्रतिनिधित्व के अभाव के लिए आलोचना का विषय रही है। यह मुख्य रूप से इसलिए है क्योंकि:
(A) महासभा के पास अत्यधिक शक्ति है।
(B) महासचिव का चुनाव वैश्विक प्रत्यक्ष मतदान द्वारा लोकतांत्रिक रीति से नहीं किया जाता है।
(C) सुरक्षा परिषद की स्थाई सदस्यता और वीटो शक्ति वर्तमान वैश्विक वास्तविकताओं को नहीं दर्शाती है।
(D) अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के सभी न्यायाधीश P5 देशों से हैं।

165. "संयुक्त राष्ट्र के भीतर कूटनीति" शब्द किस प्रक्रिया को संदर्भित करता है?
(A) गठबंधन बनाना, प्रस्तावों पर बातचीत करना और राष्ट्रीय एवं समूह हितों के लिए संयुक्त राष्ट्र मंच का लाभ उठाना।
(B) सचिवालय की आंतरिक प्रशासनिक प्रक्रियाएं।
(C) आईसीजे के समक्ष दिए गए औपचारिक कानूनी तर्क।
(D) विश्व नेताओं के साथ संयुक्त राष्ट्र महासचिव की निजी बैठकें।

166. संयुक्त राष्ट्र चार्टर संशोधन के संबंध में विकासशील देशों की एक प्रमुख मांग है:
(A) महासभा का उन्मूलन।
(B) स्थाई और अस्थाई दोनों श्रेणियों में सुरक्षा परिषद का विस्तार।
(C) न्यास परिषद को सबसे शक्तिशाली अंग बनाना।
(D) संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय को किसी विकासशील देश में स्थानांतरित करना।

167. संयुक्त राष्ट्र के वित्तपोषण के संबंध में नीचे दो कथन दिए गए हैं।
कथन I: संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना अभियानों को संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट से वित्तपोषित किया जाता है।
कथन II: शांति स्थापना का अपना पृथक बजट होता है जिसमें सदस्य देशों के लिए अंशदान का एक अलग पैमाना होता है।
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
(D) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।

168. अंतरराष्ट्रीय मामलों में भारत की "मध्यस्थ भूमिका" उसकी विदेश नीति के किस मूल सिद्धांत का विस्तार है?
(A) सैन्य श्रेष्ठता का अनुसरण।
(B) विवादों के शांतिपूर्ण समाधान में विश्वास।
(C) सैन्य गुटों का निर्माण।
(D) आर्थिक अलगाववाद।

169. निम्नलिखित में से कौन सा 'पंचशील' के पांच सिद्धांतों में से एक नहीं है?
(A) एक-दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के लिए पारस्परिक सम्मान।
(B) पारस्परिक अनाक्रमण।
(C) पूर्व-खाली हमलों का अधिकार।
(D) शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व।

170. सूची I को सूची II के साथ सुमेलित कीजिए।
सूची I: (शब्द)
P. भारतीय विदेश नीति
Q. कूटनीति
R. सुरक्षा समझौते
S. मध्यस्थ भूमिका
सूची II: (विवरण)
1. पारस्परिक रक्षा या सहयोग के लिए औपचारिक समझौते।
2. संघर्षरत पक्षों के बीच सुविधाप्रदाता के रूप में कार्य करना।
3. किसी राज्य के अंतरराष्ट्रीय संबंधों को निर्देशित करने वाली समग्र रणनीति और सिद्धांत।
4. बातचीत के संचालन की कला और अभ्यास।
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:
(A) P-3, Q-4, R-1, S-2
(B) P-1, Q-2, R-3, S-4
(C) P-3, Q-1, R-4, S-2
(D) P-4, Q-3, R-2, S-1

171. भारत की "पड़ोसी पहले" (Neighbourhood First) नीति किसे प्राथमिकता देती है?
(A) P5 देशों के साथ संबंध।
(B) निकटतम दक्षिण एशियाई क्षेत्र के देशों के साथ संबंध।
(C) आसियान (ASEAN) देशों के साथ संबंध।
(D) यूरोपीय संघ के साथ संबंध।

172. संयुक्त राष्ट्र के संदर्भ में "चार्टर संशोधन" शब्द किस प्रक्रिया को संदर्भित करता है?
(A) संयुक्त राष्ट्र की स्थापना संधि में संशोधन करना।
(B) वार्षिक बजट को संशोधित करना।
(C) संयुक्त राष्ट्र महासचिव को बदलना।
(D) किसी सदस्य देश के प्रतिनिधिमंडल की विश्वसनीयता की समीक्षा करना।

173. उत्तर-दक्षिण संवाद मुख्य रूप से अंतरराष्ट्रीय संबंधों के किस अक्ष के इर्द-गिर्द घूमता है?
(A) सैन्य-सुरक्षा
(B) आर्थिक-विकास
(C) सांस्कृतिक-धार्मिक

Click Here to Buy book on Amazon

(C) जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड
(D) पेरिस, फ्रांस

196. "सामूहिक कार्रवाई का तर्क" किस संगठन के गठन और चुनौतियों को समझने के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक है?
(A) संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद
(B) ओपेक (OPEC)
(C) जी-20 (G-20)
(D) अंतरराष्ट्रीय न्यायालय

197. अमेरिकी राज्यों के संगठन (OAS) चार्टर पर किस शहर में हस्ताक्षर किए गए थे, जिसके कारण इसे बोगोटा के चार्टर के रूप में भी जाना जाता है?
(A) सैंटियागो, चिली
(B) बोगोटा, कोलंबिया
(C) लीमा, पेरू
(D) ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना

198. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, जिनमें से:
(A) 10 स्थाई और 5 अस्थाई होते हैं।
(B) 5 स्थाई और 10 अस्थाई होते हैं।
(C) सभी 15 स्थाई होते हैं।
(D) सभी 15 अस्थाई होते हैं।

199. वह सिद्धांत कि संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों को संघर्ष का पक्ष नहीं बनना चाहिए और एक पक्ष का दूसरे पक्ष की तुलना में पक्ष नहीं लेना चाहिए, क्या कहलाता है?
(A) सहमति
(B) निष्पक्षता (Impartiality)
(C) बल का प्रयोग
(D) संप्रभुता

200. बांग्लादेश के साथ भारत के संबंध किन मुद्दों से प्रभावित रहे हैं?
(A) नदी जल बंटवारा और अवैध प्रवास।
(B) संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सीट के लिए प्रतिस्पर्धा।
(C) चीन के साथ साझा सीमा।
(D) परमाणु नीति पर असहमति।

201. 'गुजराल सिद्धांत' किसके साथ भारत के संबंधों को सुधारने के उद्देश्य से एक राजनयिक पहल थी?
(A) संयुक्त राज्य अमेरिका
(B) चीन
(C) इसके निकटवर्ती छोटे पड़ोसी देश
(D) यूरोपीय संघ

202. 'नव-उपनिवेशवाद' की अवधारणा को प्रमुखता से किसके द्वारा व्यक्त किया गया था?
(A) महात्मा गांधी
(B) क्वामे न्क्रूमा
(C) विंस्टन चर्चिल
(D) वुड्रो विल्सन

203. राउल प्रेबिश और हंस सिंगर उस संरचनावादी तर्क से जुड़े हैं जो किस सिद्धांत का आधार बनाता है?
(A) यथार्थवाद
(B) उदारवाद
(C) निर्भरता सिद्धांत
(D) रचनावाद

204. ब्रांट आयोग की रिपोर्ट, "नॉर्थ-साउथ: ए प्रोग्राम फॉर सर्वाइवल" और "कॉमन क्राइसिस", किसको बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण थीं?
(A) उत्तर-दक्षिण संवाद।
(B) विशेष रूप से दक्षिण-दक्षिण सहयोग।
(C) सैन्य गठबंधनों का गठन।
(D) संयुक्त राष्ट्र का विघटन।

NODIA

205. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में लेबल किया गया है।
अभिकथन (A): डब्ल्यूटीओ की निर्णय लेने की प्रक्रिया 'एक देश, एक वोट' के सिद्धांत पर आधारित है।
कारण (R): व्यवहार में, निर्णय आम सहमति (consensus) के माध्यम से लिए जाते हैं, जहाँ शक्तिशाली व्यापारिक राष्ट्रों का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

206. निम्नलिखित में से कौन सा संगठन मुख्य रूप से क्षेत्रीय या उप-क्षेत्रीय नहीं है?
(A) सार्क (SAARC)
(B) आसियान (ASEAN)
(C) जी-20 (G-20)
(D) ओएएस (OAS)

207. "SAFTA" किस क्षेत्रीय संगठन से जुड़ा एक व्यापार समझौता है?
(A) आसियान (ASEAN)
(B) ओपेक (OPEC)
(C) सार्क (SAARC)
(D) ओएएस (OAS)

208. कूटनीति की 'आसियान शैली' (ASEAN way) किससे बचती है?
(A) परामर्श और संवाद।
(B) आम सहमति बनाना।
(C) सार्वजनिक टकराव और कानूनी दृष्टिकोण।
(D) अहस्तक्षेप का सिद्धांत।

(C) मौजूदा ब्रेटन वुड्स प्रणाली को सुदृढ़ करना।
(D) उत्तर से विकास सहायता में वृद्धि।

255. दक्षिण-दक्षिण सहयोग को किसके परिणामस्वरूप गति मिली?
(A) उत्तर-दक्षिण संवाद की सफलता।
(B) उत्तर-दक्षिण संवाद की कथित विफलता और धीमी गति।
(C) संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का एक निर्देश।
(D) शीत युद्ध की समाप्ति।

256. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में लेबल किया गया है।
अभिकथन (A): आलोचकों का तर्क है कि डब्ल्यूटीओ की नीतियां अक्सर विकासशील देशों के हितों की तुलना में विकसित देशों के हितों का पक्ष लेती हैं।
कारण (R): बड़ी, विकसित अर्थव्यवस्थाओं के साथ बातचीत करते समय विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए डब्ल्यूटीओ के 'पारस्परिकता' के सिद्धांत को पूरा करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

257. नव-उपनिवेशवाद का केंद्रीय विचार यह है कि राजनीतिक वि-उपनिवेशीकरण ने इसे समाप्त नहीं किया:
(A) आर्थिक शोषण और निर्भरता।
(B) दास प्रथा।
(C) संप्रभु राज्यों का अस्तित्व।
(D) अंतरराष्ट्रीय व्यापार।

258. निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है?
(A) सार्क (SAARC) - बैंकॉक
(B) आसियान (ASEAN) - जकार्ता
(C) ओपेक (OPEC) - रियाद
(D) ओएएस (OAS) - रियो डी जनेरियो

259. जी-20 (G-20) और संयुक्त राष्ट्र जैसे संगठनों के बीच एक प्रमुख अंतर यह है कि जी-20:
(A) एक औपचारिक अंतरराष्ट्रीय संधि संगठन है।
(B) के पास एक शक्तिशाली स्थाई सेना है।
(C) बिना स्थाई सचिवालय के एक अनौपचारिक मंच के रूप में कार्य करता है।
(D) विशेष रूप से मानवाधिकारों के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है।

260. आसियान क्षेत्रीय मंच (ARF) किसके लिए बनाई गई संस्था का एक उदाहरण है?
(A) आर्थिक एकीकरण।
(B) सुरक्षा संवाद और विश्वास-निर्माण।
(C) अधिराष्ट्रीय (Supranational) शासन।
(D) मौद्रिक संघ।

261. 1973 के तेल संकट ने किस संगठन के अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव को नाटकीय रूप से बढ़ा दिया?
(A) ओएएस (OAS)
(B) आसियान (ASEAN)
(C) ओपेक (OPEC)
(D) सार्क (SAARC)

262. निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का प्राथमिक लक्ष्य है?
(A) राष्ट्रों के कार्यों में तालमेल बिठाने के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य करना।
(B) एक एकल वैश्विक मुद्रा स्थापित करना।
(C) सदस्य देशों की घरेलू नीतियों को विनियमित करना।
(D) एक विश्व सरकार बनाना।

263. संयुक्त राष्ट्र संघ के कामकाज के मूल्यांकन में एक बड़ी दुर्बलता इसकी है:
(A) अति-वित्तपोषित बजट।
(B) वैश्विक स्वास्थ्य मुद्दों के समाधान में असमर्थता।
(C) अपने प्रस्तावों के कार्यान्वयन के लिए सदस्य देशों की राजनीतिक इच्छाशक्ति पर निर्भरता।
(D) चर्चा के लिए मंच का अभाव।

264. संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना के संबंध में नीचे दो कथन दिए गए हैं।
कथन I: संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना एक संघर्ष प्रवर्तन तंत्र है जिसका विवरण संयुक्त राष्ट्र चार्टर में दिया गया है।
कथन II: यह एक अभिनव तंत्र है जो सहमति, निष्पक्षता और आत्मरक्षा के अतिरिक्त बल का प्रयोग न करने के सिद्धांतों पर कार्य करता है।
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
(D) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।

265. संयुक्त राष्ट्र के भीतर "शक्ति संघर्ष" मौलिक रूप से सदस्य देशों के बीच किसके लिए एक प्रतिस्पर्धा है:
(A) संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में सर्वोत्तम कार्यालय स्थान प्राप्त करना।
(B) संयुक्त राष्ट्र के एजेंडे, मानदंडों और कार्यों को अपने हितों के साथ संरेखित करने के लिए प्रभावित करना।
(C) महासभा में सर्वाधिक सीटें जीतना।
(D) अपने देश से महासचिव चुनना।

266. भारतीय विदेश नीति की निम्नलिखित विशिष्ट विशेषताओं पर विचार कीजिए:
1. पंचशील
2. गुटनिरपेक्षता

Downloaded from www.pdf.tube

220. अंतरराष्ट्रीय संबंधों के राजनीतिक-आर्थिक दृष्टिकोण इस बात पर बल देते हैं कि:
(A) आर्थिक कारक अंतरराष्ट्रीय राजनीति के लिए अप्रासंगिक हैं।
(B) राजनीतिक शक्ति और आर्थिक संपदा आंतरिक रूप से जुड़े हुए हैं और एक-दूसरे को सुदृढ़ करते हैं।
(C) सभी अंतरराष्ट्रीय संबंधों को सैन्य गणनाओं तक सीमित किया जा सकता है।
(D) राज्य ही विश्व के एकमात्र महत्वपूर्ण अभिनेता हैं।

221. उत्तर-दक्षिण संवाद में दक्षिण की मुख्य मांग क्या थी?
(A) एक अधिक न्यायसंगत वैश्विक आर्थिक प्रणाली।
(B) उत्तर से सैन्य सहायता।
(C) सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम।
(D) उत्तरी सैन्य गठबंधनों में सम्मिलित होने का अधिकार।

222. 1955 का बांडुंग सम्मेलन, जिसने दक्षिण-दक्षिण सहयोग की नींव रखी, किस देश द्वारा आयोजित किया गया था?
(A) भारत
(B) मिस्र
(C) इंडोनेशिया
(D) यूगोस्लाविया

223. डब्ल्यूटीओ (WTO) के "सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र" (MFN) सिद्धांत की आवश्यकता है कि:
(A) किसी देश के निकटतम सहयोगी को सर्वोत्तम व्यापार शर्तें मिलें।
(B) एक व्यापारिक भागीदार को दी गई कोई भी विशेष सुविधा अन्य सभी डब्ल्यूटीओ सदस्यों को दी जानी चाहिए।
(C) विकासशील देशों को सबसे अनुकूल व्यवहार मिलना चाहिए।
(D) किसी देश के अपने राष्ट्र की वस्तुओं के साथ सबसे अनुकूल व्यवहार किया जाए।

224. निर्भरता सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना यह है कि यह:
(A) विकासशील देशों की एजेंसी पर अत्यधिक बल देता है।
(B) कुछ विकासशील देशों (जैसे, एशियाई टाइगर्स) की सफलता को समझाने में विफल रहता है।
(C) अंतरराष्ट्रीय पूंजीवाद की भूमिका की उपेक्षा करता है।
(D) विकास की संभावनाओं के बारे में बहुत अधिक आशावादी है।

225. निम्नलिखित में से कौन आसियान (ASEAN) का सदस्य नहीं है?
(A) इंडोनेशिया
(B) सिंगापुर
(C) श्रीलंका
(D) वियतनाम

226. चक्रीय अध्यक्षता (Rotating presidency) निम्नलिखित में से किसकी नेतृत्व संरचना की एक विशेषता है?
(A) संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद
(B) जी-20 (G-20)
(C) ओपेक (OPEC)
(D) उपरोक्त सभी

227. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में लेबल किया गया है।
अभिकथन (A): आसियान की तुलना में सार्क एक क्षेत्रीय एकीकरण परियोजना के रूप में कम सफल रहा है।
कारण (R): इसके दो सबसे बड़े सदस्यों, भारत और पाकिस्तान के बीच निरंतर राजनीतिक संघर्ष और अविश्वास ने सहयोग को गंभीर रूप से बाधित किया है।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

NODIA

228. ओएएस (OAS) का संस्थापक चार्टर लोकतंत्र और किस पर बल देता है?
(A) अहस्तक्षेप (Non-intervention)।
(B) एकल बाजार का निर्माण।
(C) एक साझा मुद्रा।
(D) एक एकीकृत सेना।

229. संयुक्त राष्ट्र का प्राथमिक उद्देश्य जैसा कि इसके चार्टर में कहा गया है:
(A) विश्व स्तर पर मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना।
(B) अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना।
(C) एक विश्व सरकार स्थापित करना।
(D) विश्व भर में एकल कानूनी संहिता लागू करना।

230. "शांति के लिए एकता" प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा को कार्य करने का अधिकार देता है जब:
(A) कोई प्राकृतिक आपदा आती है।
(B) सुरक्षा परिषद वीटो के कारण गतिरोध में हो।
(C) आर्थिक और सामाजिक परिषद सहायता का अनुरोध करती है।
(D) एक नए सदस्य देश को प्रवेश दिया जाना हो।

231. संयुक्त राष्ट्र के शांति और विकास के परिप्रेक्ष्य सबसे समग्र रूप से किसमें समाहित हैं?
(A) सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा।
(B) एजेंडा फॉर पीस।
(C) सतत विकास लक्ष्य (SDGs)।
(D) शांति स्थापना अभियानों के नियम।

232. इनमें से कौन संयुक्त राष्ट्र चार्टर संशोधन में एक बड़ी बाधा है?
(A) चार्टर को पुनः मुद्रित करने की उच्च लागत।

209. 2008 में जी-20 (G-20) को राष्ट्राध्यक्षों के स्तर के मंच के रूप में उन्नत किया जाना किस बात की मान्यता थी?
(A) जी-7 अकेला अब वैश्विक अर्थव्यवस्था का प्रबंधन नहीं कर सकता था।
(B) आर्थिक मुद्दों की तुलना में सैन्य मुद्दे अधिक महत्वपूर्ण हो गए थे।
(C) संयुक्त राष्ट्र अप्रासंगिक हो गया था।
(D) क्षेत्रीय संगठन विफल हो रहे थे।

210. सूची I को सूची II के साथ सुमेलित कीजिए।
सूची I: (संगठन)
P. संयुक्त राष्ट्र संघ
Q. जी-20 (G-20)
R. ओपेक (OPEC)
S. सार्क (SAARC)
सूची II: (संबद्ध शब्द)
1. पेट्रोलियम नीति समन्वय
2. चार्टर संशोधन
3. ढाका शिखर सम्मेलन
4. अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग मंच
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:
(A) P-2, Q-4, R-1, S-3
(B) P-1, Q-2, R-3, S-4
(C) P-2, Q-3, R-1, S-4
(D) P-4, Q-3, R-2, S-1

211. संयुक्त राष्ट्र के किस अंग को उन क्षेत्रों की देखरेख का कार्य सौंपा गया है जो पूर्व में उपनिवेश या शासनादेश थे?
(A) सुरक्षा परिषद
(B) आर्थिक और सामाजिक परिषद
(C) न्यास परिषद (Trusteeship Council)
(D) महासभा

212. संयुक्त राष्ट्र संघ के भीतर शक्ति संघर्ष का एक प्रमुख स्रोत किसमें वीटो शक्ति के उपयोग से उत्पन्न होता है?
(A) महासभा
(B) सुरक्षा परिषद
(C) आर्थिक और सामाजिक परिषद
(D) अंतरराष्ट्रीय न्यायालय

213. "ब्लू हेलमेट" किसका बोलचाल का शब्द है?
(A) संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के कर्मचारी
(B) संयुक्त राष्ट्र शांति सेना
(C) अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश
(D) महासभा के प्रतिनिधि

214. दशकों तक भारत की विदेश नीति का आधार रहा गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) किस उद्देश्य से बनाया गया था?
(A) अमेरिका और सोवियत संघ का मुकाबला करने के लिए तीसरा सैन्य गुट बनाना।
(B) शीत युद्ध के शक्ति गुटों से दूर रहना।
(C) एशिया में आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देना।
(D) एक नई अंतरराष्ट्रीय मुद्रा स्थापित करना।

215. भारत की सुरक्षा चिंताओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत के प्रमुख सुरक्षा समझौते ऐतिहासिक रूप से पश्चिमी शक्तियों के साथ रहे हैं।
2. सीमा पार आतंकवाद एक प्राथमिक सुरक्षा खतरा बना हुआ है।
3. दक्षिण एशिया और हिंद महासागर में चीन का बढ़ता प्रभाव एक महत्वपूर्ण रणनीतिक चिंता है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3

216. कोरियाई युद्ध की वार्ताओं में भारत की भूमिका किसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है?
(A) मध्यस्थ भूमिका (Mediatory role)
(B) सैन्य हस्तक्षेपवाद
(C) आर्थिक कूटनीति
(D) गठबंधन की राजनीति

217. भारतीय विदेश नीति में "लुक ईस्ट" से "एक्ट ईस्ट" की ओर बदलाव क्या दर्शाता है?
(A) क्षेत्र से पृथक होने की इच्छा।
(B) दक्षिण-पूर्व और पूर्व एशिया के साथ जुड़ाव के लिए अधिक सक्रिय और कार्रवाई-उन्मुख दृष्टिकोण।
(C) इसके स्थान पर मध्य एशियाई देशों पर एक नया ध्यान।
(D) विशुद्ध रूप से सांस्कृतिक लक्ष्यों के पक्ष में आर्थिक लक्ष्यों का त्याग।

218. "शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के पांच सिद्धांतों" को किस रूप में भी जाना जाता है?
(A) गुजराल सिद्धांत
(B) पंचशील
(C) शिमला सिद्धांत
(D) दिल्ली घोषणा

219. विदेश नीति के संबंध में नीचे दो कथन दिए गए हैं।
कथन I: कूटनीति उन लक्ष्यों और सिद्धांतों का समूह है जो किसी देश के विदेशी संबंधों को निर्देशित करते हैं।
कथन II: विदेश नीति वह प्रक्रिया और तंत्र है जिसके द्वारा उन लक्ष्यों का अनुसरण किया जाता है।
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
(D) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।

Click Here to Buy book on Amazon

243. सार्क (SAARC) के पहले महासचिव किस देश से थे?
(A) भारत
(B) पाकिस्तान
(C) बांग्लादेश
(D) नेपाल

244. ओपेक (OPEC) सदस्य अपनी नीतियों का समन्वय किसलिए करते हैं?
(A) पेट्रोलियम उत्पादकों के लिए एक स्थिर और उचित आय सुनिश्चित करना।
(B) उपभोक्ताओं के लिए कीमतें कम करने के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना।
(C) अपनी अर्थव्यवस्थाओं को तेल निर्भरता से पृथक करना।
(D) संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित उत्पादन कोटा का पालन करना।

245. संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य "सामाजिक प्रगति और जीवन के बेहतर मानकों को बढ़ावा देना" मुख्य रूप से किस अंग के माध्यम से किया जाता है?
(A) सुरक्षा परिषद
(B) अंतरराष्ट्रीय न्यायालय
(C) आर्थिक और सामाजिक परिषद (ECOSOC)
(D) न्यास परिषद

246. वैश्विक उत्तर और वैश्विक दक्षिण के बीच संयुक्त राष्ट्र संघ के भीतर शक्ति संघर्ष किन बहसों में सबसे स्पष्ट रूप से दिखाई देता है?
(A) महासचिव की नियुक्ति।
(B) सचिवालय का बजट।
(C) विकास वित्तपोषण और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार।
(D) संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाएं।

247. संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट का वित्तपोषण किस सिद्धांत पर आधारित है?
(A) सभी सदस्य देशों से समान योगदान।
(B) केवल स्वैच्छिक योगदान।
(C) सदस्य देशों की भुगतान करने की क्षमता।
(D) किसी राज्य की सेना के आकार के आधार पर योगदान।

248. व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि (CTBT) का भारत का विरोध NPT के विरोध के समान है, जो इस आधार पर आधारित है कि यह है:
(A) पर्याप्त व्यापक नहीं है।
(B) भेदभावपूर्ण है और इसमें सार्वभौमिक निशस्त्रीकरण की समय सीमा सम्मिलित नहीं है।
(C) तकनीकी रूप से त्रुटिपूर्ण है और सभी परमाणु परीक्षणों का पता नहीं लगा सकती है।
(D) लागू करने के लिए अत्यंत खर्चीला है।

249. भारतीय कूटनीति की एक प्रमुख विशेषता 'मृदु शक्ति' (soft power) का उपयोग है, जिसमें सम्मिलित है:
(A) सैन्य धमकी।
(B) आर्थिक प्रतिबंध।
(C) सांस्कृतिक प्रभाव, लोकतांत्रिक मूल्य और विदेशी सहायता।
(D) परमाणु हथियार उपयोग करने की धमकी।

250. भारत के निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों को प्रमुख विदेश नीति पहलों (पंचशील, शिमला समझौता, लुक ईस्ट, गुजराल सिद्धांत) के साथ उनके जुड़ाव के कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए:
1. इंदिरा गांधी
2. पी.वी. नरसिम्हा राव
3. आई.के. गुजराल
4. जवाहरलाल नेहरू
(A) 4, 1, 2, 3
(B) 1, 4, 2, 3
(C) 4, 2, 1, 3
(D) 2, 3, 4, 1

251. भारतीय विदेश नीति की एक विशिष्ट विशेषता राष्ट्रीय हित और किसके अनुसरण का दोहरा दृष्टिकोण रहा है?
(A) वैश्विक प्रभुत्व की खोज।
(B) एक न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण विश्व व्यवस्था का आदर्श।
(C) एक एशियाई सैन्य गुट का गठन।
(D) आर्थिक अलगाववाद।

252. नेपाल और भूटान के साथ भारत के संबंध किसके साथ उसके संबंधों के उदाहरण हैं?
(A) प्रमुख वैश्विक शक्तियां।
(B) सुदूर अफ्रीकी राष्ट्र।
(C) निकटतम पड़ोसी जिनके साथ उसके विशेष संबंध हैं।
(D) सैन्य गठबंधन के साथी सदस्य।

253. "अंतरराष्ट्रीय संबंधों की राजनीतिक अर्थव्यवस्था" किसका अध्ययन करती है:
(A) वैश्विक क्षेत्र में राजनीतिक शक्तियां आर्थिक परिणामों को कैसे आकार देती हैं और इसके विपरीत।
(B) घरेलू राजनीति अकेले किसी राज्य के आर्थिक स्वास्थ्य को कैसे निर्धारित करती है।
(C) अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र को अंतरराष्ट्रीय राजनीति से कैसे पृथक किया जा सकता है।
(D) सभी राज्य अपनी राजनीतिक व्यवस्था की परवाह किए बिना एक जैसी आर्थिक नीतियों का पालन कैसे करते हैं।

254. निम्नलिखित में से कौन सी NIEO की प्रमुख मांग नहीं थी?
(A) बहुराष्ट्रीय निगमों (MNCs) का विनियमन।
(B) कच्चे माल और निर्मित वस्तुओं की कीमतों के बीच संबंध।

Downloaded from www.pdf.tube

185. "शांति के लिए एकता" प्रस्ताव (1950) किस संघर्ष के दौरान सुरक्षा परिषद के पक्षाघात की प्रतिक्रिया थी?
(A) वियतनाम युद्ध
(B) स्वेज संकट
(C) कोरियाई युद्ध
(D) कांगो संकट

186. कौन सा कथन संयुक्त राष्ट्र संघ के कामकाज के मूल्यांकन को सटीक रूप से दर्शाता है?
(A) यह अपने सभी प्रयासों में सार्वभौमिक रूप से सफल रहा है।
(B) यह बिना किसी महत्वपूर्ण उपलब्धि के पूरी तरह से विफल रहा है।
(C) इसका प्रदर्शन मिश्रित रहा है, सामाजिक/मानवीय क्षेत्रों में उल्लेखनीय सफलताओं के साथ लेकिन शांति और सुरक्षा बनाए रखने में चुनौतियों के साथ।
(D) इसकी प्राथमिक सफलता विश्व सरकार बनाने में रही है।

187. संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना अभियानों का वित्तपोषण अंशदान के पैमाने पर आधारित है जहाँ:
(A) सभी देश समान राशि का भुगतान करते हैं।
(B) सुरक्षा परिषद के P5 सदस्य बड़ा हिस्सा देते हैं।
(C) केवल संघर्ष में सम्मिलित देश ही अभियान के लिए भुगतान करते हैं।
(D) अभियानों को संस्थागत दान द्वारा वित्तपोषित किया जाता है।

188. भारतीय विदेश नीति की विशिष्ट विशेषताओं में से एक 'बहुध्रुवीय' विश्व व्यवस्था की वकालत रही है। इसका अर्थ है:
(A) एक ही महाशक्ति के प्रभुत्व वाली दुनिया।
(B) दो विरोधी महाशक्तियों के प्रभुत्व वाली दुनिया।
(C) शक्ति के कई केंद्रों वाली दुनिया, जो किसी एक राष्ट्र के प्रभुत्व को रोकती है।
(D) बिना किसी शक्तिशाली राज्य वाली एक अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था।

189. शीत युद्ध के दौरान पूर्व और पश्चिम के बीच भारत की मध्यस्थ भूमिका उसकी किस नीति का व्यावहारिक अनुप्रयोग थी?
(A) सोवियत संघ के साथ गठबंधन।
(B) गुटनिरपेक्षता (Non-Alignment)।
(C) आर्थिक संरक्षणवाद।
(D) क्षेत्रीय आधिपत्य।

190. निम्नलिखित में से कौन सा भारत के समुद्री वातावरण से संबंधित एक प्रमुख सुरक्षा चिंता है?
(A) हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री डकैती।
(B) आर्कटिक बर्फ का पिघलना।
(C) एंडीज पर्वतों में सीमा विवाद।
(D) मध्य यूरोप में राजनीतिक अस्थिरता।

191. 'कूटनीति' (diplomacy) शब्द को किसके प्राथमिक साधन के रूप में सबसे अच्छी तरह समझा जाता है?
(A) किसी राज्य की विदेश नीति को लागू करना।
(B) दूसरे राज्य के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करना।
(C) घरेलू आर्थिक नीति तैयार करना।
(D) राज्य की खुफिया सेवाओं का संचालन करना।

192. भारतीय विदेश नीति की विशिष्ट विशेषताओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. उपनिवेशवाद और रंगभेद का कड़ा विरोध।
2. शांतिपूर्ण साधनों के माध्यम से विवादों को सुलझाने के लिए एक ऐतिहासिक प्राथमिकता।
3. सुरक्षा के लिए सैन्य गठबंधनों में सम्मिलित होने का एक संस्थापक सिद्धांत।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3

193. सूची I को सूची II के साथ सुमेलित कीजिए।
सूची I: (अवधारणा/घटना)
P. NIEO मांग
Q. आसियान क्षेत्रीय मंच (ARF)
R. तेल की कीमतों का झटका
S. दक्षिण अमेरिकी एकीकरण
सूची II: (संबद्ध संगठन/समूह)
1. आसियान (ASEAN)
2. ओएएस (OAS)
3. जी-77 (G-77)
4. ओपेक (OPEC)
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:
(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-3, Q-1, R-4, S-2
(C) P-3, Q-4, R-1, S-2
(D) P-2, Q-1, R-4, S-3

194. नव-उपनिवेशवाद के संबंध में नीचे दो कथन दिए गए हैं।
कथन I: नव-उपनिवेशवाद उस स्थिति का वर्णन करता है जहाँ विकासशील देश, राजनीतिक रूप से स्वतंत्र होने के उपरांत भी, विकसित देशों पर आर्थिक रूप से निर्भर रहते हैं।
कथन II: निर्भरता सिद्धांत नव-उपनिवेशवाद की कार्यप्रणाली को समझने के लिए एक सैद्धांतिक ढांचा प्रदान करता है।
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
(D) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।

195. विश्व व्यापार संगठन (WTO) का मुख्यालय कहाँ है?
(A) न्यूयॉर्क, यूएसए
(B) लंदन, यूके

NODIA

3. सीटो (SEATO) और सेंटो (CENTO) में सदस्यता

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 3
(D) 1, 2 और 3

267. अपने पड़ोसियों के साथ भारत के संबंध उसकी विदेश नीति का मुख्य केंद्र हैं क्योंकि:
(A) सभी पड़ोसियों के साथ साझा आर्थिक समृद्धि है।
(B) इसके भारत की अपनी सुरक्षा और स्थिरता के लिए प्रत्यक्ष निहितार्थ हैं।
(C) दक्षिण एशियाई सैन्य गठबंधन बनाने की इच्छा है।
(D) संयुक्त राज्य अमेरिका का दबाव है।

268. सोवियत संघ द्वारा मध्यस्थता किया गया ताशकंद समझौता किस घटना के बाद एक राजनयिक प्रयास था?
(A) 1947-48 भारत-पाकिस्तान युद्ध
(B) 1962 भारत-चीन युद्ध
(C) 1965 भारत-पाकिस्तान युद्ध
(D) 1971 भारत-पाकिस्तान युद्ध

269. कूटनीति का मुख्य साधन है:
(A) बल प्रयोग
(B) प्रतिबंध
(C) बातचीत (Negotiation)
(D) प्रचार

270. सूची I को सूची II के साथ सुमेलित कीजिए।
सूची I: (नेता/सिद्धांतकार)
P. राउल प्रेबिश
Q. क्वामे न्क्रूमा
R. आई. के. गुजराल
S. विली ब्रांट
सूची II: (अवधारणा/सिद्धांत)
1. नव-उपनिवेशवाद
2. उत्तर-दक्षिण संवाद
3. निर्भरता सिद्धांत
4. गुजराल सिद्धांत
नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:
(A) P-1, Q-3, R-2, S-4
(B) P-3, Q-1, R-4, S-2
(C) P-3, Q-2, R-4, S-1
(D) P-2, Q-1, R-4, S-3

271. अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था के किस सिद्धांत में 'केंद्र' और 'परिधि' केंद्रीय अवधारणाएं हैं?
(A) उदारवाद
(B) यथार्थवाद
(C) निर्भरता सिद्धांत
(D) रचनावाद

272. नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था (NIEO) का आह्वान औपचारिक रूप से किस समूह के शिखर सम्मेलन में किया गया था?
(A) जी-7 (G-7)
(B) गुटनिरपेक्ष आंदोलन
(C) वारसॉ संधि
(D) ओईसीडी (OECD)

273. निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण-दक्षिण सहयोग का सिद्धांत नहीं है?
(A) एकजुटता
(B) पारस्परिक लाभ
(C) राष्ट्रीय संप्रभुता
(D) नीतिगत सुधार पर आधारित सशर्त सहायता

274. किस संगठन के विवाद निपटान निकाय को अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रणाली का 'सर्वोच्च रत्न' कहा गया है?
(A) अंकटाड (UNCTAD)
(B) डब्ल्यूटीओ (WTO)
(C) नाफ्टा (NAFTA)
(D) अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF)

275. जोफ़ान (ZOPFAN - शांति, स्वतंत्रता और तटस्थता का क्षेत्र) किस संगठन से जुड़ी एक घोषणा है?
(A) सार्क (SAARC)
(B) ओएएस (OAS)
(C) आसियान (ASEAN)
(D) जी-20 (G-20)

276. जी-20 (G-20) के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
(A) इसमें विकसित और विकासशील दोनों देश सम्मिलित हैं।
(B) इसका गठन 1999 में वित्त मंत्री स्तर पर किया गया था।
(C) इसके पास कानूनी रूप से बाध्यकारी चार्टर और प्रवर्तन शक्तियां हैं।
(D) यह वैश्विक अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रमुख मुद्दों का समाधान करता है।

277. संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं में निम्नलिखित को छोड़कर सभी शामिल हैं:
(A) चीनी
(B) फ्रांसीसी
(C) जर्मन
(D) स्पेनिश

278. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में लेबल किया गया है।
अभिकथन (A): संयुक्त राष्ट्र महासभा को अक्सर 'विश्व की संसद' कहा जाता है।
कारण (R): महासभा में सभी सदस्य देशों का समान वोट होता

Click Here to Buy book on Amazon

अनिवार्य हिस्सा माना जाता है। ये अंग सामूहिक रुप से वैश्विक शासन के विभिन्न पहलुओं का प्रबंधन करते हैं।

35. (A) 'A' और 'R' दोनों सही हैं और 'R', 'A' की सही व्याख्या है।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की संरचना की आलोचना अक्सर इसके अलोकतांत्रिक स्वरुप के कारण की जाती है। वीटो शक्ति वाले पांच स्थाई सदस्य आज भी 1945 के शक्ति संतुलन का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह वर्तमान समय की बदलती भू-राजनीतिक वास्तविकताओं और उभरती हुई शक्तियों की उपेक्षा करता है। इस अप्रतिनिधिक ढांचे के कारण परिषद की निर्णय लेने की प्रक्रिया अक्सर बाधित होती है। सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग इसी विसंगति को दूर करने और इसे अधिक लोकतांत्रिक बनाने के लिए है। यह अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की विश्वसनीयता और प्रासंगिकता बनाए रखने हेतु अनिवार्य है।

36. (C) आर्थिक और सामाजिक परिषद (ECOSOC)
आर्थिक और सामाजिक परिषद संयुक्त राष्ट्र की विभिन्न विशिष्ट एजेंसियों और कार्यक्रमों के कार्यों में समन्वय स्थापित करने के लिए उत्तरदायी है। यह अंग वैश्विक स्तर पर गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य और सतत विकास जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर नीतिगत समीक्षा और संवाद को बढ़ावा देता है। यह महासभा के साथ मिलकर आर्थिक और सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करता है। यह अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से लोगों के जीवन स्तर को सुधारने और मानवीय समस्याओं के समाधान में सहायक होता है। यह वैश्विक कल्याण और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण स्तंभ है।

37. (D) सुरक्षा परिषद
सुरक्षा परिषद में शक्ति संघर्ष और कूटनीति का सबसे तीव्र रूप देखने को मिलता है। पांच स्थाई सदस्यों के पास वीटो शक्ति होने के कारण, किसी भी महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय मुद्दे पर निर्णय लेना अत्यंत चुनौतीपूर्ण होता है। ये सदस्य अक्सर अपने राष्ट्रीय हितों और रणनीतिक उद्देश्यों के अनुसार मतदान करते हैं। यह अंग वैश्विक राजनीति में महाशक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा और कूटनीतिक सौदेबाजी का मुख्य केंद्र है। परिषद की प्रभावशीलता अक्सर इन शक्तिशाली राष्ट्रों के बीच आपसी सहमति पर निर्भर करती है। यह अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और संघर्ष प्रबंधन की सबसे निर्णायक संस्था है।

38. (A) चार्टर में स्पष्ट रूप से नहीं है लेकिन एक कार्यात्मक उपकरण के रूप में विकसित हुई है।
शांति स्थापना की अवधारणा संयुक्त राष्ट्र चार्टर के किसी विशिष्ट अध्याय में स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं है। समय के साथ संघर्षों को रोकने और शांति समझौतों को लागू करने के लिए इसे एक लचीले और व्यावहारिक साधन के रूप में विकसित किया गया। इसे अक्सर 'अध्याय छह और आधा' के रूप में वर्णित किया जाता है क्योंकि यह विवादों के शांतिपूर्ण समाधान और सैन्य कार्रवाई के बीच का मार्ग है। यह अंतरराष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र का सबसे प्रभावी उपकरण बन गया है। यह वैश्विक संघर्षों को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

39. (C) कुछ सदस्य देशों द्वारा निर्धारित अंशदान के भुगतान में देरी और भुगतान न करना।
संयुक्त राष्ट्र की वित्तीय स्थिति अक्सर सदस्य राष्ट्रों द्वारा समय पर अंशदान न देने के कारण संकट में रहती है। कई देश राजनीतिक कारणों या घरेलू समस्याओं के चलते अपना निर्धारित हिस्सा देने में देरी करते हैं। इससे संगठन के शांति स्थापना अभियानों और विकासात्मक कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है। वित्तीय निर्भरता के कारण संयुक्त राष्ट्र के लिए स्वतंत्र रुप से निर्णय लेना और प्रभावी ढंग से कार्य करना कठिन हो जाता है। यह मुद्दा संगठन की प्रशासनिक क्षमता और उसकी स्वतंत्रता को भी प्रभावित करता है। यह वैश्विक सहयोग के लिए एक गंभीर चुनौती है।

40. (C) संशोधन को दो-तिहाई सदस्यों द्वारा अनुसमर्थित किए जाने की आवश्यकता, जिसमें सुरक्षा परिषद के सभी पांच स्थाई सदस्य शामिल हों।
संयुक्त राष्ट्र चार्टर में किसी भी बदलाव के लिए अत्यंत कठोर प्रक्रिया निर्धारित की गई है। किसी भी संशोधन को वैध होने के लिए सुरक्षा परिषद के सभी पांच स्थाई सदस्यों की सहमति अनिवार्य है। यदि एक भी स्थाई सदस्य वीटो करता है, तो संशोधन पारित नहीं हो सकता। यह शर्त सुरक्षा परिषद के ढांचे में सुधार करने या वीटो शक्ति को कम करने के प्रयासों में सबसे बड़ी बाधा है। इसके कारण चार्टर को वर्तमान वैश्विक वास्तविकताओं के अनुरूप बदलना अत्यंत कठिन है। यह संगठन के लोकतांत्रिक सुधारों की राह में एक स्थाई संवैधानिक अवरोध है।

41. (C) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
संयुक्त राष्ट्र का यह मानना है कि शांति और विकास एक-दूसरे के पूरक हैं और इनके बिना स्थिरता संभव नहीं है। बुतरोस बुतरोस-घाली के 'एजेंडा फॉर पीस' में केवल सैन्य हस्तक्षेप ही नहीं, बल्कि शांति निर्माण और कूटनीति पर भी व्यापक बल दिया गया था। विकास को शांति की आधारशिला माना गया है क्योंकि गरीबी और असमानता अक्सर संघर्षों को जन्म देती हैं। इसलिए, संगठन के दृष्टिकोण में सुरक्षा और आर्थिक उन्नति को हमेशा परस्पर निर्भर प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। यह समग्र दृष्टिकोण अंतरराष्ट्रीय शांति के लिए एक स्थाई समाधान प्रस्तुत करता है।

42. (D) महासभा
"शांति के लिए एकता" प्रस्ताव महासभा को वह शक्ति प्रदान करता है जहाँ वह अंतरराष्ट्रीय शांति के मुद्दों पर निर्णय ले सकती है। यह तब होता है जब सुरक्षा परिषद के स्थाई सदस्यों के बीच वीटो के कारण गतिरोध पैदा हो जाता है। इस प्रस्ताव के माध्यम से महासभा सदस्य देशों को शांति बहाल करने के लिए सामूहिक उपायों की सिफारिश कर सकती है। यह संयुक्त राष्ट्र को संकट के समय में निष्क्रिय होने से बचाने और वैश्विक सुरक्षा के लिए वैकल्पिक मार्ग प्रदान करने का प्रयास है। यह अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में महासभा की भूमिका को सुदृढ़ करता है।

NODIA

3. "ब्लू हेलमेट"
4. सामाजिक और आर्थिक समन्वय

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए:
(A) P-2, Q-3, R-4, S-1
(B) P-1, Q-2, R-3, S-4
(C) P-2, Q-4, R-3, S-1
(D) P-4, Q-3, R-1, S-2

291. गुटनिरपेक्ष आंदोलन के गठन में भारत की भूमिका किसका उदाहरण है?
(A) गठबंधन बनाने और नए स्वतंत्र देशों के लिए एक तीसरा मार्ग प्रदान करने के प्रयास।
(B) विश्व मामलों से स्वयं को पृथक करने की इच्छा।
(C) पश्चिमी शक्तियों के साथ समझौते।
(D) किसी विशिष्ट संघर्ष में मध्यस्थ भूमिका।

292. भारत के लिए उसके पड़ोस से उत्पन्न होने वाली एक प्राथमिक सुरक्षा चिंता है:
(A) अफगानिस्तान में अस्थिरता और इसके क्षेत्रीय निहितार्थ।
(B) ब्राजील की आर्थिक नीतियां।
(C) स्कैंडिनेविया में राजनीतिक घटनाक्रम।
(D) अमेरिका और चीन के बीच व्यापार विवाद।

293. 'कूटनीति' शब्द की उत्पत्ति किस विषय से संबंधित शब्द से हुई है?
(A) युद्ध का संचालन।
(B) दस्तावेजों को मोड़ने की प्रक्रिया।
(C) किलाबंदी का निर्माण।
(D) करों का संग्रह।

294. भारतीय विदेश नीति की एक विशिष्ट विशेषता गुटनिरपेक्षता से किसमें इसका विकास है?
(A) अमेरिका के साथ एक औपचारिक गठबंधन।
(B) मुद्रा-आधारित सहभागिता पर आधारित एक बहु-पक्षीय (multi-aligned) दृष्टिकोण।
(C) अलगाववाद की नीति।
(D) रूसी नेतृत्व वाले सैन्य गुट में सम्मिलित होना।

295. संयुक्त राष्ट्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. संयुक्त राष्ट्र चार्टर सुरक्षा परिषद को अंतरराष्ट्रीय शांति बनाए रखने की प्राथमिक जिम्मेदारी देता है।
2. संयुक्त राष्ट्र के पास महासचिव की सीधी कमान के तहत एक स्थाई सेना है।
3. चार्टर संशोधन के लिए सुरक्षा परिषद के सभी पांच स्थाई सदस्यों की स्वीकृति आवश्यक है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से सही हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3

296. निर्भरता सिद्धांत का केंद्रीय तर्क यह है कि परिधि में अल्पविकास है:
(A) आधुनिकीकरण के पथ पर एक अस्थायी चरण।
(B) केंद्र द्वारा सक्रिय रूप से निर्मित और बनाए रखी गई स्थिति।
(C) केवल त्रुटिपूर्ण घरेलू नीतियों का परिणाम।
(D) भौगोलिक प्रतिकूलता का परिणाम।

297. जी-20 (G-20), जी-7 की तुलना में विश्व अर्थव्यवस्था का अधिक प्रतिनिधि समूह है क्योंकि इसमें सम्मिलित हैं:
(A) संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य।
(B) प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाएं।
(C) अफ्रीकी संघ के सभी सदस्य।
(D) केवल दक्षिणी गोलार्ध के देश।

298. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन (A) और दूसरे को कारण (R) के रूप में लेबल किया गया है।
अभिकथन (A): भारत संयुक्त राष्ट्र सुधारों, विशेष रूप से सुरक्षा परिषद के सुधारों का प्रबल समर्थक रहा है।
कारण (R): भारत का मानना है कि यूएनएससी की वर्तमान संरचना अलोकतांत्रिक है और समकालीन भू-राजनीतिक वास्तविकताओं को नहीं दर्शाती है।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

299. पंचशील का मूल सिद्धांत, "एक-दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के लिए पारस्परिक सम्मान" किसके द्वारा सबसे प्रत्यक्ष तौर पर चुनौती दी जाती है?
(A) सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम।
(B) व्यापार समझौते।
(C) सीमा विवाद और सीमा पार आतंकवाद।
(D) राजनयिक वार्ता।

300. भारत के लिए 'लुक ईस्ट' से 'एक्ट ईस्ट' नीति में संक्रमण का अर्थ किसकी ओर बदलाव है?
(A) आसियान क्षेत्र के साथ कम जुड़ाव।
(B) एक अधिक सक्रिय, परियोजना-आधारित और परिणाम-उन्मुख जुड़ाव।
(C) क्षेत्र में केवल सैन्य समझौतों पर ध्यान केंद्रित करना।
(D) सांस्कृतिक संबंधों के पक्ष में आर्थिक संबंधों का त्याग।

www.nodia.in

Downloaded from www.pdf.tube

परमाणु संपन्न देशों के पक्ष में झुकी हुई है और अन्य देशों की सुरक्षा चिंताओं की उपेक्षा करती है। भारत का रुख यह है कि निशस्त्रीकरण की प्रक्रिया सार्वभौमिक होनी चाहिए। अतः, भारत की निशस्त्रीकरण के प्रति प्रतिबद्धता उसकी सुरक्षा आवश्यकताओं के साथ संतुलित है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा और वैश्विक शांति के बीच एक तार्किक समन्वय है।

52. (B) सीमा पार आतंकवाद।
भारत के लिए उसके निकटतम पड़ोस में सीमा पार आतंकवाद सबसे गंभीर और निरंतर बनी रहने वाली सुरक्षा चुनौती है। यह समस्या न केवल आंतरिक शांति को बाधित करती है, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता को भी खतरे में डालती है। आतंकवाद के कारण भारत को अपनी सीमाओं पर अत्यधिक सैन्य सतर्कता और संसाधन तैनात करने पड़ते हैं। पड़ोस से संचालित होने वाले आतंकी समूहों से निपटना भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक प्राथमिकता है। यह मुद्दा अक्सर पड़ोसी देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों में तनाव का कारण बनता है। यह राष्ट्रीय अखंडता के लिए एक निरंतर गंभीर खतरा है।

53. (C) चीन
पंचशील समझौता 1954 में भारत और चीन के बीच हस्ताक्षरित किया गया था, जो शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के पांच सिद्धांतों को प्रतिपादित करता है। इन सिद्धांतों में एक-दूसरे की अखंडता का सम्मान और आंतरिक मामलों में अहस्तक्षेप मुख्य थे। यद्यपि बाद के वर्षों में इन सिद्धांतों को चुनौतियों का सामना करना पड़ा, फिर भी ये भारतीय विदेश नीति के नैतिक आधार बने रहे। यह समझौता एशिया के दो बड़े राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों के लिए एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक प्रयास के रूप में देखा जाता है। यह अंतरराष्ट्रीय संबंधों में शांतिपूर्ण संवाद का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उदाहरण है।

54. (A) बातचीत और संवाद के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय संबंधों का संचालन।
कूटनीति किसी देश की विदेश नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक शांतिपूर्ण और रणनीतिक साधन है। इसमें बातचीत, समझौतों और प्रतिनिधित्व के माध्यम से अन्य देशों के साथ संबंधों को प्रबंधित किया जाता है। एक प्रभावी कूटनीति सैन्य संघर्षों को टालने और आपसी हितों को बढ़ावा देने में सहायक होती है। यह अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में सहयोग और संवाद का वातावरण तैयार करने की कला है। भारत ने अपनी कूटनीति का उपयोग सदैव वैश्विक शांति और राष्ट्रहित के बीच संतुलन बनाने के लिए किया है। यह अंतरराष्ट्रीय मंच पर देश की प्रभावशीलता और प्रतिष्ठा को बढ़ाता है।

55. (C) सुरक्षा के प्राथमिक साधन के रूप में सैन्य गठबंधनों का अनुसरण।
भारतीय विदेश नीति की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसने कभी भी सुरक्षा के लिए किसी सैन्य गठबंधन में शामिल होना स्वीकार नहीं किया। भारत ने अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखने के लिए गुटनिरपेक्षता को प्राथमिकता दी है। इसके विपरीत, भारत ने सदैव विवादों के शांतिपूर्ण समाधान, उपनिवेशवाद के विरोध और संयुक्त राष्ट्र के सुदृढ़ीकरण पर बल दिया है। सैन्य गुटों से दूरी बनाए रखना भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक स्वतंत्र निर्णय लेने वाली शक्ति के रूप में स्थापित करने में सहायक रहा है। यह राष्ट्रीय गरिमा और वैश्विक न्याय के सिद्धांतों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दर्शाता है।

56. (C) दक्षिण-पूर्व और पूर्व एशिया
भारत की 'पूर्व की ओर देखो नीति' का मुख्य उद्देश्य दक्षिण-पूर्व और पूर्व एशियाई देशों के साथ आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को गहरा करना था। 1990 के दशक में शुरू हुई यह नीति भारत के आर्थिक उदारीकरण के प्रयासों का एक हिस्सा थी। बाद में इसे 'एक्ट ईस्ट' नीति में बदलकर और अधिक सक्रिय बनाया गया, जिसमें सुरक्षा और कनेक्टिविटी पर विशेष ध्यान दिया गया। यह नीति भारत के इस क्षेत्र में बढ़ते प्रभाव और आसियान देशों के साथ मजबूत साझेदारी को दर्शाती है। यह भारत की वैश्विक आर्थिक भागीदारी और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए एक रणनीतिक बदलाव है।

57. (B) पाकिस्तान के साथ संघर्षों को सुलझाने के कूटनीतिक प्रयास।
ताशकंद और शिमला समझौते भारत द्वारा पाकिस्तान के साथ युद्ध के बाद शांति स्थापित करने के महत्वपूर्ण कूटनीतिक प्रयास थे। इन समझौतों का उद्देश्य द्विपक्षीय विवादों को बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के बातचीत के माध्यम से हल करना था। शिमला समझौते ने विशेष रूप से नियंत्रण रेखा के सम्मान और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की आवश्यकता पर बल दिया। यद्यपि इन समझौतों के पूर्ण कार्यान्वयन में चुनौतियां रहीं, लेकिन ये दोनों देशों के बीच संबंधों को सुधारने के लिए भारत की निरंतर कूटनीतिक प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हैं। यह शांति और स्थिरता की दिशा में एक गंभीर प्रयास था।

58. (C) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
भारतीय कूटनीति अपनी 'मृदु शक्ति' के माध्यम से दुनिया भर में अपना प्रभाव बढ़ाने पर बल देती है, जिसमें भारत की संस्कृति और लोकतांत्रिक मूल्य महत्वपूर्ण हैं। हालांकि, यह कहना गलत है कि भारत की विदेश नीति 1947 से पूरी तरह अपरिवर्तित रही है। समय के साथ, वैश्विक स्थितियों और राष्ट्रीय हितों के अनुसार इसमें कई महत्वपूर्ण बदलाव और नवाचार हुए हैं। भारत ने अपनी मूल मान्यताओं को बनाए रखते हुए बदलती विश्व व्यवस्था के साथ अपनी कूटनीतिक रणनीतियों को कुशलतापूर्वक अनुकूलित किया है। यह नीति की गतिशीलता और समय की आवश्यकता के अनुसार इसके विकास को दर्शाता है।

59. (B) छोटे पड़ोसियों को सद्भावना के साथ एकतरफा रियायतें देनी चाहिए।
गुजराल सिद्धांत का मूल मंत्र यह है कि भारत को अपने छोटे पड़ोसियों के साथ उदार व्यवहार करना चाहिए। इस नीति के तहत भारत इन देशों से किसी तत्काल लाभ या पारस्परिकता की अपेक्षा किए बिना सहयोग प्रदान करता है। यह दृष्टिकोण इस विश्वास पर आधारित है कि पड़ोसियों के साथ मधुर संबंध भारत की अपनी सुरक्षा और समृद्धि के लिए आवश्यक हैं। इस सिद्धांत ने दक्षिण एशिया में विश्वास की कमी को दूर करने और

NODIA

9. (C) यह मानता है कि अंतरराष्ट्रीय पूंजीवाद वैश्विक विकास के लिए एक कल्याणकारी शक्ति है।
निर्भरता सिद्धांत इस विचार को सिरे से नकारता है कि अंतरराष्ट्रीय पूंजीवाद विकास के लिए एक कल्याणकारी शक्ति है। इसके विपरीत, यह तर्क देता है कि वैश्विक पूंजीवादी ढांचा परिधि के देशों के शोषण पर आधारित है। यह सिद्धांत विश्व को केंद्र और परिधि में विभाजित मानता है, जहाँ धन का प्रवाह हमेशा केंद्र की ओर होता है। विकासशील देशों के लिए आत्मनिर्भरता प्राप्त करना इस व्यवस्था के भीतर काफी चुनौतीपूर्ण कार्य माना गया है। यह व्यवस्था निर्धन राष्ट्रों को स्थाई पिछड़ेपन की ओर धकेलती है।

10. (A) P-3, Q-4, R-1, S-2
अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था में विभिन्न अवधारणाएं वैश्विक संबंधों को परिभाषित करती हैं। नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का विचार जी-77 देशों के प्रयासों से उभरा था। दक्षिण-दक्षिण सहयोग की जड़ें बांडुंग सम्मेलन की एकजुटता में देखी जा सकती हैं। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना मराकेश समझौते के माध्यम से हुई थी। निर्भरता सिद्धांत को प्रतिपादित करने में राउल प्रेबिश का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। ये सभी तत्व वैश्विक शासन और विकास की संरचना को निर्धारित करते हैं। ये राष्ट्रों के बीच संबंधों को नया आयाम प्रदान करते हैं।

11. (D) ग्रुप ऑफ 77 (G-77)
ग्रुप ऑफ 77 विकासशील देशों का एक प्रमुख गठबंधन है जो अंतरराष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर उनकी सामूहिक आवाज को मजबूत करता है। यह संगठन मुख्य रूप से दक्षिण-दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देने और वैश्विक व्यापार वार्ताओं में विकासशील देशों के हितों की रक्षा करने के लिए कार्य करता है। इसकी स्थापना के माध्यम से निर्धन राष्ट्रों ने अपनी आर्थिक आत्मनिर्भरता और तकनीकी आदान-प्रदान के लिए एक साझा मंच विकसित करने का सफल प्रयास किया है। यह समूह संयुक्त राष्ट्र में विकासशील राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व करने वाला सबसे बड़ा निकाय है।

12. (B) नव-उपनिवेशवाद
जब अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान ऋण के बदले विकासशील देशों पर कठोर शर्तें थोपते हैं, तो इसे नव-उपनिवेशवाद के रूप में देखा जाता है। इसमें सार्वजनिक उद्यमों का निजीकरण और सरकारी खर्च में कटौती जैसे उपाय शामिल होते हैं, जो इन देशों की संप्रभुता को प्रभावित करते हैं। यह प्रक्रिया प्रत्यक्ष नियंत्रण के बिना राष्ट्रों की आर्थिक नीतियों को प्रभावित करने का एक साधन है। यह दर्शाता है कि कैसे आर्थिक निर्भरता राजनीतिक स्वायत्तता को प्रभावी ढंग से सीमित कर सकती है। यह व्यवस्था विकासशील राष्ट्रों के विकास को बाधित करती है।

13. (C) ब्रांट आयोग
विली ब्रांट की अध्यक्षता वाले ब्रांट आयोग ने अपनी रिपोर्ट में उत्तर-दक्षिण संवाद को वैश्विक स्थिरता के लिए आवश्यक बताया था। इस रिपोर्ट ने धनी और निर्धन देशों के बीच बढ़ती असमानता की ओर ध्यान आकर्षित किया और आपसी सहयोग के नए मार्ग प्रशस्त किए। इसने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुधार और विकास सहायता बढ़ाने का आह्वान किया। इसके प्रकाशन के बाद वैश्विक स्तर पर विकासशील देशों की समस्याओं पर चर्चा की गति में वृद्धि हुई। यह रिपोर्ट वैश्विक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज सिद्ध हुई।

14. (C) केवल 1 और 3
विश्व व्यापार संगठन की स्थापना गेट के उत्तराधिकारी के रूप में अंतरराष्ट्रीय व्यापार को व्यवस्थित करने के लिए की गई थी। इसके कामकाज में 'सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र' का सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो व्यापारिक भेदभाव को रोकने का कार्य करता है। हालांकि, इस संगठन में निर्णय आमतौर पर आम सहमति से लिए जाते हैं, न कि केवल बहुमत के मतदान से। यह संरचना सुनिश्चित करती है कि सभी सदस्य राष्ट्रों की चिंताओं को व्यापारिक नीतियों के निर्धारण में उचित महत्व दिया जाए। यह बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली में विश्वास बनाए रखने के लिए आवश्यक है।

15. (A) विकसित, औद्योगिक और पूंजीवादी राष्ट्र।
निर्भरता सिद्धांत के अनुसार 'केंद्र' उन विकसित और औद्योगिक राष्ट्रों को संदर्भित करता है जो वैश्विक आर्थिक प्रणाली पर नियंत्रण रखते हैं। ये राष्ट्र परिधि के देशों से कच्चे माल और सस्ते श्रम का लाभ उठाते हैं। केंद्र के राष्ट्रों की समृद्धि काफी हद तक विकासशील राष्ट्रों के संसाधनों के शोषण पर टिकी होती है। यह अवधारणा वैश्विक स्तर पर धन और शक्ति के असमान वितरण को दर्शाती है, जहाँ तकनीक और पूंजी केंद्र में केंद्रित रहती है। यह व्यवस्था परिधि के देशों को आर्थिक रूप से पंगु बना देती है।

16. (B) आसियान (ASEAN)
दक्षिण-पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संगठन की स्थापना 1967 में बैंकॉक घोषणा के माध्यम से हुई थी। इस क्षेत्रीय संगठन का मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों के बीच आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना है। इसकी स्थापना क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए एक सामूहिक प्रयास के रूप में की गई थी। इसके पांच संस्थापक सदस्यों ने क्षेत्रीय चुनौतियों का सामना करने के लिए इस मंच को एक मजबूत आधार प्रदान करने का कार्य किया। वर्तमान में यह संगठन वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

17. (C) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
ओपेक की स्थापना पेट्रोलियम नीतियों के समन्वय और सदस्य देशों के हितों की रक्षा के लिए की गई थी। यह संगठन वैश्विक तेल बाजार में मूल्य स्थिरता और आपूर्ति सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 1970 के दशक के बाद भी वैश्विक ऊर्जा राजनीति में इसका प्रभाव अत्यंत महत्वपूर्ण बना रहा है। यह कहना गलत है कि इसका प्रभाव कम हो गया है, क्योंकि आज भी इसकी उत्पादन नीतियां विश्व भर की आर्थिक गतिविधियों को गहराई से प्रभावित करती हैं। यह वैश्विक

Click Here to Buy book on Amazon

उत्तर (व्याख्या सहित)

1. (B) विकासशील देशों के पक्ष में वैश्विक आर्थिक प्रणाली का पुनर्गठन करना।
नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का मुख्य लक्ष्य विश्व की आर्थिक प्रणाली में व्यापक संरचनात्मक बदलाव करना था। इसका प्राथमिक उद्देश्य विकासशील देशों के लिए बेहतर व्यापार शर्तें सुनिश्चित करना और उनके प्राकृतिक संसाधनों पर संप्रभुता को मजबूत करना था। यह व्यवस्था धनी और निर्धन देशों के बीच बढ़ते आर्थिक अंतर को कम करने का गंभीर प्रयास करती है। इसमें वैश्विक वित्तीय संस्थानों में सुधार और विकासशील देशों को तकनीकी सहायता प्रदान करने पर बल दिया जाता है।

2. (D) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।
अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से राष्ट्रों के धन और शक्ति के बीच के जटिल अंतर्संबंधों का अध्ययन करती है। यह विश्लेषण करता है कि राजनीतिक निर्णय आर्थिक गतिविधियों को कैसे प्रभावित करते हैं और आर्थिक परिस्थितियां अंतरराष्ट्रीय राजनीति को कैसे दिशा देती हैं। केवल आर्थिक नीतियों का अध्ययन करना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि वे सदैव राजनीतिक उद्देश्यों से जुड़ी होती हैं। यह क्षेत्र राज्यों और वैश्विक बाजारों के बीच के संबंधों को समझने में सहायता प्रदान करता है।

3. (C) अपने प्राकृतिक संसाधनों पर विकासशील देशों की संप्रभुता को सीमित करना।
नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य विकासशील देशों को उनके संसाधनों पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान करना था। यह व्यवस्था विकसित देशों से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और विकास सहायता में वृद्धि की मांग करती है। इसके अतिरिक्त, यह कच्चे माल के लिए न्यायसंगत मूल्य सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। संप्रभुता को सीमित करना इसके लक्ष्यों के पूर्णतः विपरीत है, क्योंकि यह राष्ट्रों की आर्थिक स्वतंत्रता को पुनः स्थापित करने का प्रयास था। यह वैश्विक समानता के प्रति एक महत्वपूर्ण पहल थी।

4. (D) विकसित, औद्योगिक देश और विकासशील देश।
उत्तर-दक्षिण संवाद का तात्पर्य मुख्य रूप से दुनिया के धनी औद्योगिक राष्ट्रों और निर्धन विकासशील देशों के बीच होने वाली वार्ताओं से है। इसमें वैश्विक अर्थव्यवस्था, व्यापार असंतुलन और वित्तीय सहायता जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाती है। 'उत्तर' विकसित राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि 'दक्षिण' अल्पविकसित और विकासशील राष्ट्रों का समूह है। इस संवाद का प्राथमिक उद्देश्य एक अधिक न्यायपूर्ण और न्यायसंगत अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का निर्माण करना है। यह वैश्विक सहयोग को मजबूत करने का आधार है।

5. (C) इसमें राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में विकासशील देशों के बीच सहयोग शामिल है।
दक्षिण-दक्षिण सहयोग विकासशील देशों के बीच संसाधनों, प्रौद्योगिकी और ज्ञान को साझा करने का एक प्रभावी मंच है। यह सहयोग केवल आर्थिक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में भी व्यापक रूप से फैला हुआ है। यह सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है और विकसित देशों पर ऐतिहासिक निर्भरता को कम करता है। यह राष्ट्रों के बीच समानता और एकजुटता के सिद्धांतों पर आधारित है, जो वैश्विक दक्षिण को सशक्त बनाकर अंतरराष्ट्रीय राजनीति में संतुलन स्थापित करता है।

6. (A) 'A' और 'R' दोनों सही हैं और 'R', 'A' की सही व्याख्या है।
निर्भरता सिद्धांत के अनुसार विकासशील देशों का अल्पविकास अंतरराष्ट्रीय पूंजीवादी व्यवस्था का परिणाम है। यह सिद्धांत मानता है कि दुनिया एक केंद्र और परिधि में विभाजित है। केंद्र के विकसित राष्ट्र अपनी समृद्धि के लिए परिधि के संसाधनों का निरंतर शोषण करते हैं। यह विचार आधुनिकीकरण के उन सिद्धांतों की आलोचना करता है जो मानते हैं कि सभी देश एक ही मार्ग पर चलकर विकसित हो सकते हैं। यह वैश्विक असमानता के संरचनात्मक कारणों पर बल देकर विकास की नई व्याख्या करता है।

7. (D) अंतरराष्ट्रीय व्यापार को विनियमित करना और वाणिज्य के सुचारू प्रवाह को सुनिश्चित करना।
विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना और सदस्य देशों के बीच व्यापारिक विवादों को सुलझाना है। यह व्यापार समझौतों के कार्यान्वयन और प्रशासन के लिए एक सुव्यवस्थित मंच प्रदान करता है। यह संगठन सुनिश्चित करता है कि वैश्विक वाणिज्य बिना किसी बाधा के सुचारू रूप से चलता रहे। इसके नियम व्यापारिक नीतियों में पारदर्शिता और निष्पक्षता को बढ़ावा देते हैं। यह वैश्विक आर्थिक शासन में एक निर्णायक भूमिका निभाता है और बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को मजबूती प्रदान करता है।

8. (A) आर्थिक और सांस्कृतिक माध्यमों से किसी विकासशील देश पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण।
नव-उपनिवेशवाद एक ऐसी स्थिति है जहाँ शक्तिशाली राष्ट्र प्रत्यक्ष सैन्य शासन के बिना अन्य देशों पर अपना प्रभाव बनाए रखते हैं। यह प्रभाव मुख्य रूप से आर्थिक निवेश, ऋण और सांस्कृतिक माध्यमों से स्थापित किया जाता है। इसके माध्यम से विकासशील देशों की नीतियों को विकसित राष्ट्रों के हितों के अनुसार नियंत्रित किया जाता है। यद्यपि ये देश राजनीतिक रूप से स्वतंत्र होते हैं, परंतु उनकी आर्थिक स्वायत्तता बाहरी शक्तियों द्वारा गहराई से प्रभावित होती है। यह आधुनिक समय में शोषण का एक सूक्ष्म और जटिल स्वरूप है।

NODIA

26. (A) इसके सदस्य वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के लगभग 85% का प्रतिनिधित्व करते हैं।
जी-20 समूह की महत्ता इस तथ्य से स्पष्ट होती है कि इसके सदस्य देश दुनिया की अधिकांश आर्थिक शक्ति को नियंत्रित करते हैं। यह समूह वैश्विक व्यापार के 75% और दुनिया की दो-तिहाई जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें केवल विकसित राष्ट्र ही नहीं, बल्कि भारत और ब्राजील जैसी प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाएं भी शामिल हैं। इसकी निर्णय लेने की प्रक्रिया और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव इसे अंतरराष्ट्रीय मंच पर एक अत्यंत शक्तिशाली और अनिवार्य निकाय बनाता है। यह वैश्विक चुनौतियों के समाधान हेतु एक समावेशी और प्रभावी मंच सिद्ध हुआ है।

27. (A) 4, 1, 2, 3
क्षेत्रीय संगठनों की स्थापना अलग-अलग समय पर हुई थी। अमेरिकी राज्यों के संगठन की स्थापना 1948 में हुई थी। इसके पश्चात ओपेक का गठन 1960 में हुआ, जो तेल उत्पादक देशों का समूह है। आसियान की स्थापना 1967 में बैंकॉक घोषणा के माध्यम से की गई थी। अंत में, सार्क का गठन 1985 में दक्षिण एशियाई देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए हुआ था। यह कालक्रम वैश्विक और क्षेत्रीय राजनीति में सहयोग के बदलते स्वरूप को दर्शाता है। ये संगठन अपने-अपने क्षेत्रों में शांति और विकास के लिए समर्पित रहे हैं।

28. (B) अहस्तक्षेप, आम सहमति बनाना और परामर्श।
'आसियान शैली' राजनयिक व्यवहार की एक विशिष्ट पद्धति है जो सदस्य राष्ट्रों के आंतरिक मामलों में अहस्तक्षेप पर बल देती है। यह कानूनी रूप से बाध्यकारी निर्णयों के स्थान पर आम सहमति और अनौपचारिक परामर्श को प्राथमिकता देती है। यह दृष्टिकोण विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने और क्षेत्रीय एकता बनाए रखने में सहायक रहा है। यह सदस्य देशों की संप्रभुता का सम्मान करते हुए सहयोग को बढ़ावा देने की एक सफल और अद्वितीय एशियाई पद्धति मानी जाती है। यह क्षेत्रीय स्थिरता और परस्पर विश्वास को सुदृढ़ करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है।

29. (C) संगठन के भीतर संयुक्त राज्य अमेरिका का ऐतिहासिक प्रभुत्व।
अमेरिकी राज्यों के संगठन की एक प्रमुख चुनौती इसके भीतर संयुक्त राज्य अमेरिका का अत्यधिक राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव रहा है। कई लैटिन अमेरिकी देशों ने अक्सर यह महसूस किया है कि संगठन की नीतियां अमेरिकी हितों के पक्ष में अधिक झुकी हुई होती हैं। इस प्रभुत्व ने संगठन के भीतर शक्ति संतुलन और निर्णय लेने की प्रक्रिया में निष्पक्षता को लेकर विवाद पैदा किए हैं। इसने सदस्य देशों के बीच पूर्ण विश्वास और समान भागीदारी को बाधित किया है। यह क्षेत्रीय सहयोग की राह में एक महत्वपूर्ण बाधा और चुनौती बनी हुई है।

30. (A) P-3, Q-1, R-4, S-2
विभिन्न क्षेत्रीय संगठन विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों पर केंद्रित हैं। सार्क मुख्य रूप से दक्षिण एशिया के देशों के बीच सहयोग का मंच है। आसियान का ध्यान दक्षिण-पूर्व एशिया के विकास और स्थिरता पर है। ओपेक मुख्य रूप से मध्य पूर्व के तेल उत्पादक देशों का प्रतिनिधित्व करता है, हालांकि इसमें अन्य क्षेत्रों के देश भी शामिल हैं। अमेरिकी राज्यों का संगठन पश्चिमी गोलार्ध के देशों के बीच राजनीतिक और आर्थिक संबंधों को प्रबंधित करने के लिए बनाया गया है। ये सभी संगठन क्षेत्रीय शांति और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए कार्य करते हैं।

31. (B) वैश्विक वित्तीय संकट।
वर्ष 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट ने दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को साथ आने के लिए विवश किया। इसी संकट की प्रतिक्रिया के रूप में जी-20 को वित्त मंत्रियों के स्तर से बढ़ाकर राष्ट्राध्यक्षों के शिखर सम्मेलन के स्तर तक लाया गया। इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली में सुधार करना और भविष्य में ऐसे संकटों को रोकने के लिए वैश्विक नीतिगत समन्वय स्थापित करना था। इसने वैश्विक आर्थिक शासन में उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं की भूमिका को और अधिक महत्वपूर्ण बना दिया। यह वैश्विक सहयोग के इतिहास में एक निर्णायक और ऐतिहासिक मोड़ सिद्ध हुआ।

32. (C) केवल 1 और 3
आसियान क्षेत्रीय मंच एशिया-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा और राजनीतिक संवाद के लिए एक महत्वपूर्ण तंत्र है। जी-20 में विकसित और विकासशील दोनों तरह की प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं, जो इसे व्यापक और प्रतिनिधि समूह बनाती हैं। हालांकि, सार्क ने अभी तक कोई साझा मुद्रा आरंभ नहीं की है और इस दिशा में कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है। ये संगठन अपनी विशिष्ट संरचनाओं और उद्देश्यों के माध्यम से क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता में योगदान देने का प्रयास करते हैं। यह अंतरराष्ट्रीय संबंधों में सहयोग के विभिन्न स्तरों और क्षेत्रों को स्पष्ट करता है।

33. (B) आने वाली पीढ़ियों को युद्ध की विभीषिका से बचाना।
संयुक्त राष्ट्र चार्टर की प्रस्तावना का मुख्य उद्देश्य वैश्विक शांति सुनिश्चित करना और भविष्य में होने वाले भीषण युद्धों को रोकना है। द्वितीय विश्व युद्ध की विनाशकारी घटनाओं के बाद, राष्ट्रों ने सामूहिक रूप से यह संकल्प लिया था कि वे विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करेंगे। चार्टर में मौलिक मानवाधिकारों, गरिमा और राष्ट्रों की समानता के प्रति विश्वास को भी दोहराया गया है। यह दस्तावेज अंतरराष्ट्रीय सहयोग और न्याय पर आधारित एक नई विश्व व्यवस्था की आधारशिला प्रस्तुत करता है। यह मानवता के बेहतर और सुरक्षित भविष्य के लिए एक वैश्विक संकल्प है।

34. (D) छह
संयुक्त राष्ट्र संघ के सुचारु संचालन के लिए इसे छह मुख्य अंगों में विभाजित किया गया है। इनमें महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, सचिवालय, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय और न्यास परिषद शामिल हैं। प्रत्येक अंग की अपनी विशिष्ट जिम्मेदारियां और कार्यक्षेत्र हैं जो अंतरराष्ट्रीय शांति, विकास और न्याय को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किए गए हैं। हालांकि न्यास परिषद ने अपना कार्य लगभग पूरा कर लिया है, लेकिन यह अभी भी संगठन की मूल संरचना का एक

NODIA

है, जो संप्रभु समानता के सिद्धांत को दर्शाता है।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

279. संयुक्त राष्ट्र के शांति स्थापना अभियान अक्सर अहस्तक्षेप के सिद्धांत और किसके बीच दुविधा में फंस जाते हैं:
(A) नागरिकों की रक्षा करने की आवश्यकता।
(B) लाभ उत्पन्न करने की आवश्यकता।
(C) राज्य संप्रभुता का सिद्धांत।
(D) महासचिव की मांग।

280. भारतीय कूटनीति की प्राथमिक भूमिका क्या है?
(A) शांतिपूर्ण साधनों के माध्यम से भारत के राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाना।
(B) घरेलू नीति तैयार करना।
(C) भारतीय सशस्त्र बलों की कमान संभाल करना।
(D) भारत की खुफिया एजेंसियों का संचालन करना।

281. भारत और पाकिस्तान के बीच 1972 के शिमला समझौते ने किस पर बल दिया था?
(A) तीसरे पक्ष की मध्यस्थता के माध्यम से मुद्दों का समाधान।
(B) बाहरी हस्तक्षेप के बिना द्विपक्षीय रूप से मुद्दों का समाधान।
(C) एक संयुक्त सैन्य कमान का निर्माण।
(D) कश्मीर विवाद का तत्काल निपटारा।

282. शीत युद्ध के बाद के विश्व में गुटनिरपेक्ष दृष्टिकोण की निरंतरता किस भारतीय विदेश नीति अवधारणा में परिलक्षित होती है?
(A) पूर्व की ओर देखो नीति
(B) रणनीतिक स्वायत्तता (Strategic Autonomy)
(C) गुजराल सिद्धांत
(D) पंचशील

283. भारत की "पूर्व की ओर देखो" नीति को संचालित करने वाले मुख्य कारकों में से एक था:
(A) सोवियत संघ का पतन और नए आर्थिक भागीदारों की आवश्यकता।
(B) पाकिस्तान के विरुद्ध सैन्य गठबंधन बनाने की इच्छा।
(C) एशिया के साथ जुड़ने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका का दबाव।
(D) एक मॉडल के रूप में सार्क (SAARC) की सफलता।

284. वाक्यांश "उत्तर-दक्षिण संवाद" किसके बीच संघर्ष को संदर्भित करता है?
(A) उत्तर और दक्षिण कोरिया।
(B) अमीर, औद्योगिक राष्ट्र और निर्धन, विकासशील राष्ट्र।
(C) अमेरिकी गृहयुद्ध के दौरान उत्तरी और दक्षिणी राज्य।
(D) जलवायु परिवर्तन को लेकर उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के देश।

285. डब्ल्यूटीओ (WTO) के संबंध में नीचे दो कथन दिए गए हैं।
कथन I: डब्ल्यूटीओ का लक्ष्य अंतरराष्ट्रीय व्यापार की बाधाओं को कम करना है।
कथन II: डब्ल्यूटीओ वार्ता का दोहा दौर शीघ्र और सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
(D) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।

286. नव-उपनिवेशवाद निम्नलिखित में से किसको छोड़कर सभी तंत्रों के माध्यम से कार्य करता है?
(A) बहुराष्ट्रीय निगम
(B) अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान
(C) प्रत्यक्ष सैन्य अधिकार और प्रशासन
(D) सांस्कृतिक साम्राज्यवाद

287. निम्नलिखित में से कौन ओपेक (OPEC) का सदस्य नहीं है?
(A) सऊदी अरब
(B) वेनेजुएला
(C) मैक्सिको
(D) नाइजीरिया

288. सार्क (SAARC) की मुख्य संरचनात्मक दुर्बलता जो इसकी प्रगति में बाधा डालती है, वह है:
(A) वह सिद्धांत कि द्विपक्षीय और विवादास्पद मुद्दों पर चर्चा नहीं की जानी है।
(B) एक साझा भाषा का अभाव।
(C) क्षेत्र में धर्मों की विविधता।
(D) क्षेत्र का भौगोलिक आकार।

289. संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग अंतरराष्ट्रीय न्यायालय से किसी भी कानूनी प्रश्न पर परामर्शदात्री राय मांग सकता है?
(A) महासभा और सुरक्षा परिषद।
(B) केवल सुरक्षा परिषद।
(C) केवल महासचिव।
(D) केवल न्यास परिषद।

290. सूची I को सूची II के साथ सुमेलित कीजिए।
सूची I: (संयुक्त राष्ट्र निकाय/अवधारणा)
P. सुरक्षा परिषद
Q. शांति स्थापना
R. आर्थिक और सामाजिक परिषद
S. अंतरराष्ट्रीय न्यायालय
सूची II: (मुख्य कार्य/विशेषता)
1. "द हेग"
2. वीटो शक्ति

Downloaded from www.pdf.tube

43. (C) विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)
विश्व स्वास्थ्य संगठन संयुक्त राष्ट्र का एक मुख्य अंग नहीं है, बल्कि यह एक विशिष्ट एजेंसी है। संयुक्त राष्ट्र के केवल छह मुख्य अंग हैं जो इसकी स्थापना संधि द्वारा निर्धारित किए गए थे। डब्ल्यूएचओ जैसे संगठन अपनी स्वतंत्र संरचना रखते हैं और विशिष्ट क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्रदान करते हैं। वे आर्थिक और सामाजिक परिषद के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र के साथ समन्वय करते हैं। प्रमुख अंगों का कार्य पूरे संगठन के प्रशासन, न्याय और वैश्विक सुरक्षा के व्यापक नीतिगत ढांचे को संचालित करना होता है। यह संयुक्त राष्ट्र की संगठनात्मक संरचना और उसके कार्यक्षेत्र को स्पष्ट करता है।

44. (D) सुरक्षा परिषद के भीतर अलोकतांत्रिक प्रकृति और वीटो शक्ति।
संयुक्त राष्ट्र में "लोकतांत्रिक घाटे" की आलोचना मुख्य रूप से सुरक्षा परिषद की वीटो शक्ति पर केंद्रित है। यह शक्ति पांच देशों को पूरे विश्व के सामूहिक निर्णयों को रोकने की अनुमति देती है, जो समानता के लोकतांत्रिक सिद्धांत के विरुद्ध है। यह संरचना 21वीं सदी की बहुध्रुवीय दुनिया का उचित प्रतिनिधित्व नहीं करती है। इस कारण से, कई राष्ट्र इसे अलोकतांत्रिक और भेदभावपूर्ण मानते हैं। सुरक्षा परिषद में सुधार के बिना संयुक्त राष्ट्र की लोकतांत्रिक वैधता पर प्रश्नचिह्न लगा रहता है। यह अंतरराष्ट्रीय शासन प्रणाली में समानता और समावेशिता को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।

45. (A) उन्हें सभी सदस्य देशों पर अनिवार्य अंशदान के माध्यम से वित्तपोषित किया जाता है, जिसमें सुरक्षा परिषद के स्थाई सदस्य अधिक हिस्सा देते हैं।
संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना अभियानों के लिए सदस्य राष्ट्रों को एक विशेष सूत्र के आधार पर अंशदान देना होता है। इस सूत्र के अनुसार, आर्थिक रूप से संपन्न और सुरक्षा परिषद के स्थाई सदस्यों पर अधिक वित्तीय भार डाला जाता है। यह अनिवार्य अंशदान संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट से अलग होता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शांति अभियानों के लिए पर्याप्त और निरंतर संसाधन उपलब्ध रहें। यह वैश्विक सुरक्षा के लिए राष्ट्रों की सामूहिक जिम्मेदारी को भी दर्शाता है। यह अंतरराष्ट्रीय शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए एक वित्तीय आधार प्रदान करता है।

46. (B) गुटनिरपेक्षता (Non-Alignment)
गुटनिरपेक्षता भारतीय विदेश नीति का एक आधारभूत सिद्धांत है जो किसी भी सैन्य गुट में शामिल न होने पर बल देता है। यह नीति भारत को अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी स्वतंत्र राय रखने और राष्ट्रहित में निर्णय लेने की स्वायत्तता प्रदान करती है। शीत युद्ध के दौरान, भारत ने महाशक्तियों के बीच शक्ति संघर्ष से दूर रहकर वैश्विक शांति को बढ़ावा दिया। यह सिद्धांत आज भी भारत को एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में अपनी भूमिका प्रभावी ढंग से निभाने में सहायता प्रदान करता है। यह राष्ट्रीय संप्रभुता और रणनीतिक स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है।

47. (D) कोरियाई युद्ध
कोरियाई युद्ध के दौरान भारत ने संघर्षरत पक्षों के बीच संवाद स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण मध्यस्थ भूमिका निभाई थी। भारत ने युद्धविराम और युद्धबंदियों की वापसी के लिए रचनात्मक प्रस्ताव पेश किए थे, जिन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया। इस भूमिका ने भारत की एक निष्पक्ष और शांतिप्रिय राष्ट्र के रूप में छवि को मजबूत किया। यह घटना दर्शाती है कि कैसे भारत ने अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का उपयोग वैश्विक तनावों को कम करने और मानवीय संकटों को सुलझाने के लिए किया था। यह अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में भारत के बढ़ते प्रभाव और जिम्मेदारी का प्रतीक था।

48. (C) केवल 1 और 3
भारतीय विदेश नीति पंचशील के सिद्धांतों पर आधारित है, जो शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व और संप्रभुता के सम्मान पर बल देते हैं। भारत ने सदैव एक बहुध्रुवीय विश्व का समर्थन किया है जहाँ शक्ति का वितरण संतुलित हो। स्वतंत्रता के बाद से, भारत ने कभी भी किसी सैन्य गुट का हिस्सा बनना स्वीकार नहीं किया और अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखी। यह निरंतरता भारत को वैश्विक मंच पर एक विश्वसनीय और स्वतंत्र शक्ति के रूप में स्थापित करने में सहायक सिद्ध हुई है। यह भारत की वैश्विक छवि को शांतिप्रिय और न्यायपूर्ण राष्ट्र के रूप में सुदृढ़ करता है।

49. (C) भूटान
भारत और भूटान के बीच के संबंध विश्वास और आपसी सहयोग पर आधारित एक अनूठी साझेदारी का उदाहरण हैं। भूटान भारत की 'पड़ोसी पहले' नीति का एक प्रमुख स्तंभ है, जहां दोनों देश सुरक्षा और विकास के क्षेत्र में निकटता से जुड़े हुए हैं। भारत ने भूटान के बुनियादी ढांचे और जलविद्युत क्षेत्र के विकास में निरंतर महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह द्विपक्षीय संबंध क्षेत्रीय स्थिरता के लिए आदर्श माने जाते हैं और भारत के अपने पड़ोसियों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। यह मित्रता और परस्पर सहयोग की एक दीर्घकालिक और सशक्त परंपरा है।

50. (B) छोटे, निकटवर्ती पड़ोसी देश
गुजराल सिद्धांत भारत की विदेश नीति का एक अभिनव दृष्टिकोण है जो छोटे पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को बेहतर बनाने पर केंद्रित है। इस सिद्धांत के अनुसार, भारत को दक्षिण एशिया के बड़े भाई के रूप में इन देशों को एकतरफा रियायतें देनी चाहिए। इसमें पारस्परिकता की मांग किए बिना सद्भावना और विश्वास निर्माण को प्राथमिकता दी जाती है। इसका उद्देश्य क्षेत्र में शांति और सहयोग का वातावरण तैयार करना है जिससे भारत की अपनी सुरक्षा और विकास के लक्ष्य सुलभ हो सकें। यह दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय एकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

51. (C) A सही है लेकिन R गलत है।
भारत ने हमेशा वैश्विक स्तर पर पूर्ण और भेदभाव रहित परमाणु निशस्त्रीकरण का पुरजोर समर्थन किया है। हालांकि, भारत ने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने से स्पष्ट इनकार कर दिया क्योंकि वह इसे भेदभावपूर्ण मानता है। यह संधि

NODIA

अर्थव्यवस्था की स्थिरता के लिए एक निर्णायक कारक बना हुआ है।

18. (A) काठमांडू, नेपाल
दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। यह सचिवालय सदस्य देशों के बीच सहयोग और संचार के मुख्य केंद्र के रूप में कार्य करता है। इसकी स्थापना का उद्देश्य दक्षिण एशिया के देशों के बीच शांति, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना था। सचिवालय संगठन की विभिन्न गतिविधियों, सम्मेलनों और विकास कार्यक्रमों के समन्वय की जिम्मेदारी निभाता है, जिससे क्षेत्रीय एकीकरण के प्रयासों को बल मिलता है। यह दक्षिण एशियाई राष्ट्रों के बीच कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करने का आधार प्रदान करता है।

19. (A) 'A' और 'R' दोनों सही हैं और 'R', 'A' की सही व्याख्या है।
सार्क की प्रगति में सबसे बड़ी बाधा इसके सदस्य देशों के बीच चल रहे द्विपक्षीय और राजनीतिक विवाद रहे हैं। संगठन के चार्टर में यह स्पष्ट प्रावधान है कि विवादास्पद और द्विपक्षीय मुद्दों को बैठकों में नहीं उठाया जाएगा। इस सीमा के कारण सदस्य राष्ट्र महत्वपूर्ण क्षेत्रीय समस्याओं पर खुलकर चर्चा करने में असमर्थ रहते हैं। राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी और आपसी अविश्वास ने सार्क की प्रभावशीलता और इसके विकास लक्ष्यों की प्राप्ति को अत्यंत सीमित कर दिया है। यह क्षेत्रीय सहयोग की संभावनाओं को बाधित करने वाला मुख्य कारक है।

20. (D) वियतनाम
आसियान की स्थापना के समय थाईलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, इंडोनेशिया और मलेशिया इसके संस्थापक सदस्य थे। वियतनाम इस संगठन में बहुत बाद में, वर्ष 1995 में शामिल हुआ था। संस्थापक देशों ने बैंकॉक घोषणा के माध्यम से क्षेत्रीय सहयोग की नींव रखी थी। वर्तमान में वियतनाम इस संगठन का एक महत्वपूर्ण सक्रिय सदस्य है, लेकिन यह उन मूल राष्ट्रों में शामिल नहीं था जिन्होंने 1967 में इस क्षेत्रीय मंच की कल्पना की थी और इसे आरंभ किया था। यह संगठन के विस्तार और क्षेत्रीय समावेशिता के विकास को दर्शाता है।

21. (C) एक वस्तु उत्पादक संघ (कार्टेल)
पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन एक वस्तु उत्पादक संघ के रूप में कार्य करता है, जो तेल की कीमतों को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। यह अपने सदस्यों के बीच तेल उत्पादन की मात्रा निर्धारित करके वैश्विक बाजार में स्थिरता लाने का कार्य करता है। एक कार्टेल के रूप में यह अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की आपूर्ति और मूल्य को प्रभावित करने की महत्वपूर्ण शक्ति रखता है। इसका मुख्य उद्देश्य उत्पादकों के लिए उचित आय और उपभोक्ताओं के लिए स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित करना है। यह वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

22. (B) राजनीतिक चर्चा और पश्चिमी गोलार्ध के मामलों के लिए एक क्षेत्रीय मंच के रूप में कार्य करना।
अमेरिकी राज्यों के संगठन का प्राथमिक उद्देश्य पश्चिमी गोलार्ध के देशों के बीच शांति और सुरक्षा को मजबूत करना है। यह संगठन लोकतंत्र को बढ़ावा देने, मानवाधिकारों की रक्षा करने और सदस्य देशों के बीच विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए एक मंच प्रदान करता है। यह क्षेत्रीय सहयोग के माध्यम से आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को प्रोत्साहित करता है। यह अमेरिकी महाद्वीप के राष्ट्रों के बीच एकजुटता और सहयोग को मजबूत करने वाली एक प्रमुख संस्था है। इसकी भूमिका क्षेत्रीय स्थिरता और विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है।

23. (D) प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए एक प्रमुख मंच।
जी-20 विश्व की सबसे बड़ी विकसित और उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक महत्वपूर्ण अनौपचारिक समूह है। यह वैश्विक आर्थिक स्थिरता, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और सतत विकास जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के लिए एक मंच प्रदान करता है। इसमें दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुख राष्ट्र शामिल हैं, जो सामूहिक रूप से वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसका उद्देश्य वैश्विक वित्तीय चुनौतियों का सामना करने के लिए सदस्य देशों के बीच प्रभावी नीतिगत समन्वय बनाना है। यह वर्तमान वैश्विक आर्थिक शासन का एक अत्यंत प्रभावी माध्यम है।

24. (A) क्षेत्र में आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना।
आसियान का मुख्य लक्ष्य दक्षिण-पूर्व एशिया में आर्थिक समृद्धि और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना है। यह संगठन क्षेत्रीय शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए कानून के शासन और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों के प्रति सम्मान पर बल देता है। इसके माध्यम से सदस्य राष्ट्र शिक्षा, शोध और तकनीकी क्षेत्रों में एक-दूसरे की सहायता करते हैं। इसका उद्देश्य इस क्षेत्र को एक प्रतिस्पर्धी और एकीकृत आर्थिक बाजार के रूप में वैश्विक स्तर पर स्थापित करना है। यह क्षेत्रीय विकास और सामूहिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य करता है।

25. (C) म्यांमार
दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव और अफगानिस्तान शामिल हैं। म्यांमार दक्षिण-पूर्व एशिया का हिस्सा है और यह आसियान का सदस्य है, न कि सार्क का। सार्क का भौगोलिक केंद्र मुख्य रूप से दक्षिण एशिया है, जहाँ सदस्य राष्ट्र साझा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों के आधार पर सहयोग करते हैं। म्यांमार का संगठन में शामिल न होना इसके भौगोलिक और राजनीतिक वर्गीकरण को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। यह दक्षिण एशिया की क्षेत्रीय सीमाओं और कूटनीतिक पहचान को स्पष्ट करने वाला एक महत्वपूर्ण तथ्य है।

Click Here to Buy book on Amazon

क्षेत्रीय सहयोग को एक नई दिशा देने का प्रयास किया है। यह पड़ोसी राष्ट्रों के साथ सौहार्दपूर्ण और मजबूत संबंधों की नींव रखता है।

60. (B) अनसुलझे सीमा और क्षेत्रीय मुद्दे।
भारत और चीन के बीच सुरक्षा चिंताओं का मुख्य कारण हजारों किलोमीटर लंबी अनसुलझी सीमा है। क्षेत्रीय दावों और वास्तविक नियंत्रण रेखा पर होने वाले विवादों ने दोनों देशों के संबंधों में हमेशा तनाव बनाए रखा है। सीमावर्ती क्षेत्रों में सैन्य बुनियादी ढांचे का विकास और शक्ति संतुलन की होड़ इन चिंताओं को और अधिक गहरा करती है। ये मुद्दे न केवल द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित करते हैं, बल्कि पूरे दक्षिण एशियाई क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति पर भी व्यापक प्रभाव डालते हैं। यह एशियाई राजनीति में रणनीतिक स्थिरता और शांति के लिए एक निरंतर बनी रहने वाली चुनौती है।

61. (C) NIEO - ब्रेटन वुड्स संस्थान
नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की मांग वास्तव में ब्रेटन वुड्स संस्थानों द्वारा स्थापित आर्थिक ढांचे की आलोचना और उसमें सुधार के लिए थी। ब्रेटन वुड्स प्रणाली को विकसित देशों के हितों का पोषक माना गया था, जबकि यह व्यवस्था विकासशील देशों के लिए न्यायसंगत प्रणाली चाहती थी। अन्य युग्म सही हैं क्योंकि निर्भरता सिद्धांत केंद्र-परिधि संबंधों पर आधारित है, दक्षिण-दक्षिण सहयोग जी-77 से जुड़ा है और डब्ल्यूटीओ में व्यापार वार्ता का दोहा दौर एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया रही है। यह वैश्विक आर्थिक सुधार और न्यायसंगत व्यापारिक नियमों की दिशा में एक संगठित प्रयास को दर्शाता है।

62. (B) गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) और जी-77 (G-77) द्वारा।
नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की मांग मुख्य रूप से उन देशों द्वारा की गई थी जो उपनिवेशवाद से स्वतंत्र हुए थे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन और जी-77 ने इस मांग को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर संगठित रूप से प्रस्तुत किया। इनका तर्क था कि मौजूदा वैश्विक आर्थिक ढांचा विकासशील राष्ट्रों के विरुद्ध पक्षपाती है। इन समूहों ने वैश्विक संसाधनों के न्यायसंगत वितरण और व्यापारिक नियमों में सुधार के लिए निरंतर दबाव बनाया। यह सामूहिक प्रयास वैश्विक दक्षिण की आर्थिक संप्रभुता प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण था। यह राष्ट्रों के बीच आर्थिक समानता और न्याय को बढ़ावा देने का संकल्प था।

63. (B) धन और शक्ति
अंतरराष्ट्रीय संबंधों की राजनीतिक अर्थव्यवस्था एक ऐसा क्षेत्र है जो आर्थिक संसाधनों और राजनीतिक प्रभाव के बीच के अंतर्संबंधों का गहन अध्ययन करता है। यह विश्लेषण करता है कि राज्य अपनी राजनीतिक शक्ति का उपयोग धन अर्जित करने के लिए कैसे करते हैं और आर्थिक समृद्धि राजनीतिक प्रभाव को कैसे बढ़ाती है। इस अध्ययन में वैश्विक बाजार, व्यापारिक नीतियां और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। यह समझने में मदद करता है कि विश्व में संसाधनों का वितरण और शक्ति का संचालन कैसे होता है। यह अंतरराष्ट्रीय संबंधों के वास्तविक आधारों का तार्किक विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

64. (A) 2, 4, 3, 1
इन घटनाओं का सही कालक्रम वैश्विक आर्थिक इतिहास के महत्वपूर्ण चरणों को दर्शाता है। सबसे पहले 1964 में पहला अंकटाड सम्मेलन आयोजित किया गया था। उसी वर्ष जी-77 का भी गठन हुआ था। इसके पश्चात 1980 में ब्रांट आयोग की महत्वपूर्ण रिपोर्ट प्रकाशित हुई, जिसने उत्तर-दक्षिण संवाद पर बल दिया। अंत में, 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई, जिसने वैश्विक व्यापार को नए नियम प्रदान किए। यह क्रम आर्थिक सहयोग और सुधार के लिए बढ़ते वैश्विक प्रयासों को स्पष्ट करता है। यह अंतरराष्ट्रीय आर्थिक शासन के विकास का एक व्यवस्थित और तार्किक मार्ग है।

65. (C) आर्थिक निर्भरता और सांस्कृतिक साम्राज्यवाद।
नव-उपनिवेशवाद प्रत्यक्ष नियंत्रण के स्थान पर अप्रत्यक्ष माध्यमों से पूर्व उपनिवेशों का शोषण जारी रखने की एक रणनीति है। इसमें विकसित देश अपनी आर्थिक शक्ति, बहुराष्ट्रीय कंपनियों और तकनीकी श्रेष्ठता का उपयोग करके विकासशील राष्ट्रों की नीतियों को प्रभावित करते हैं। इसके साथ ही, सांस्कृतिक साम्राज्यवाद के माध्यम से वे अपनी जीवनशैली और मूल्यों को थोपते हैं, जिससे बौद्धिक निर्भरता बढ़ती है। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि राजनीतिक स्वतंत्रता के बावजूद ये राष्ट्र आर्थिक रूप से शक्तिशाली देशों के अधीन बने रहें। यह आधुनिक युग में संप्रभुता को चुनौती देने वाला एक सूक्ष्म और जटिल तंत्र है।

66. (C) उरुग्वे दौर
उरुग्वे दौर की वार्ताएं गेट के इतिहास में सबसे लंबी और व्यापक थीं, जो 1986 से 1994 तक चलीं। इन्हीं वार्ताओं के परिणामस्वरूप 1995 में विश्व व्यापार संगठन का निर्माण हुआ। इस दौर ने न केवल वस्तुओं के व्यापार बल्कि सेवाओं, बौद्धिक संपदा और कृषि जैसे नए क्षेत्रों को भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार नियमों के दायरे में लाया। इसने वैश्विक व्यापार शासन के लिए एक स्थाई और अधिक शक्तिशाली संस्थागत ढांचा प्रदान किया, जिसने पिछली गेट प्रणाली की सीमाओं को सफलतापूर्वक दूर किया। यह अंतरराष्ट्रीय वाणिज्य और आर्थिक सहयोग के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ सिद्ध हुआ।

67. (C) A सही है लेकिन R गलत है।
दक्षिण-दक्षिण सहयोग विकासशील देशों के बीच एकजुटता और समानता पर आधारित एक महत्वपूर्ण साझेदारी है। इसका मुख्य उद्देश्य इन देशों की सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ाना और एक-दूसरे के अनुभवों से सीखना है। हालांकि, यह उत्तर-दक्षिण सहयोग का विकल्प नहीं है, बल्कि उसके पूरक के रूप में कार्य करता है। विकासशील देशों को अभी भी विकसित राष्ट्रों से निवेश, तकनीक और सहायता की आवश्यकता होती है। अतः, यह सहयोग वैश्विक विकास के लिए एक अतिरिक्त और आवश्यक आयाम प्रस्तुत करता है। यह विकासशील राष्ट्रों की सामूहिक शक्ति और स्वायत्तता को वैश्विक स्तर पर सुदृढ़ करने का प्रयास है।

NODIA

उसे ज्यों का त्यों बनाए रखना। अतः, केवल नव-उपनिवेशवाद से संबंधित कथन ही पूर्णतः सत्य और तर्कसंगत प्रतीत होता है। यह अवधारणा अंतरराष्ट्रीय संबंधों में आर्थिक शक्ति के सूक्ष्म और अप्रत्यक्ष रूपों को समझने के लिए अनिवार्य है। यह स्वतंत्र राष्ट्रों की आर्थिक स्वायत्तता के संघर्ष को प्रतिबिंबित करता है।

99. (B) एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जो आंतरिक रूप से जुड़े हुए हैं।
निर्भरता सिद्धांतकारों का तर्क है कि विकसित देशों की समृद्धि और विकासशील देशों का पिछड़ापन दो अलग-अलग घटनाएं नहीं हैं। वे एक-दूसरे से इस प्रकार जुड़े हैं कि केंद्र का विकास परिधि के संसाधनों और श्रम के शोषण पर निर्भर है। यह एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ एक पक्ष का लाभ अनिवार्य रूप से दूसरे पक्ष की हानि का कारण बनता है। यह सिद्धांत वैश्विक असमानता को एक ही ऐतिहासिक और आर्थिक प्रक्रिया का परिणाम मानता है, जिसमें संरचनात्मक परिवर्तन के बिना सुधार संभव नहीं है। यह अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंधों के भीतर मौजूद शोषणकारी प्रवृत्तियों का गहराई से विश्लेषण करता है। यह वैश्विक पूंजीवाद के नकारात्मक प्रभावों को उजागर करने वाला एक महत्वपूर्ण सैद्धांतिक ढांचा प्रस्तुत करता है।

100. (C) एशिया-प्रशांत में सुरक्षा संवाद और विश्वास-निर्माण।
आसियान क्षेत्रीय मंच एशिया-प्रशांत क्षेत्र में बहुपक्षीय सुरक्षा चर्चा के लिए एक प्रमुख संस्थान है। इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों के बीच राजनीतिक और सुरक्षा चिंताओं पर संवाद को बढ़ावा देना और आपसी विश्वास कायम करना है। यह मंच निवारक कूटनीति के माध्यम से संघर्षों को टालने का प्रयास करता है। इसमें आसियान सदस्यों के अतिरिक्त कई बड़ी वैश्विक शक्तियां भी भाग लेती हैं। यह क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण सहकारी ढांचा प्रदान करने में सहायक सिद्ध हुआ है। यह अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए संवाद की महत्ता को रेखांकित करता है। यह एशिया-प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था का एक अनिवार्य और प्रभावी स्तंभ है।

101. (D) ओएएस (OAS)
अमेरिकी राज्यों के संगठन के चार्टर में लोकतंत्र को बढ़ावा देने और उसकी रक्षा करने को एक अनिवार्य कर्तव्य माना गया है। यह संगठन पश्चिमी गोलार्ध में लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने के लिए सक्रिय रूप से कार्य करता है। इसके पास उन देशों के विरुद्ध कार्रवाई करने का भी अधिकार है जहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था में बाधा आती है। अन्य संगठनों जैसे ओपेक या आसियान के प्राथमिक उद्देश्य मुख्य रूप से आर्थिक या क्षेत्रीय सहयोग हैं। ओएएस की यह विशेषता इसे अन्य क्षेत्रीय निकायों से अलग और विशिष्ट बनाती है। यह क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए लोकतांत्रिक संस्थानों की मजबूती और उनके संरक्षण को सर्वोपरि मानता है। यह पश्चिमी गोलार्ध के राष्ट्रों के बीच लोकतांत्रिक एकजुटता का प्रतीक है।

102. (A) 'A' और 'R' दोनों सही हैं और 'R', 'A' की सही व्याख्या है।
जी-20 आज वैश्विक आर्थिक शासन में जी-7 की तुलना में अधिक प्रभावशाली माना जाता है क्योंकि इसकी सदस्यता अधिक व्यापक है। इसमें विकसित राष्ट्रों के साथ-साथ भारत और ब्राजील जैसी प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाएं भी शामिल हैं, जो वर्तमान विश्व की आर्थिक वास्तविकताओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। जी-7 केवल कुछ चुनिंदा धनी राष्ट्रों का समूह है, जो अब अकेले वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने में सक्षम नहीं है। जी-20 की समावेशी प्रकृति इसे वैश्विक वित्तीय निर्णयों के लिए अधिक वैध और प्रभावी मंच बनाती है। यह अंतरराष्ट्रीय आर्थिक नीतियों के निर्धारण में विकासशील देशों की बढ़ती भूमिका को भी स्पष्ट करता है। यह वैश्विक सहयोग के बदलते स्वरूप का एक आदर्श उदाहरण है।

103. (B) भारत और पाकिस्तान के बीच राजनीतिक तनाव।
सार्क की धीमी प्रगति का सबसे प्रमुख कारण भारत और पाकिस्तान के बीच निरंतर बना रहने वाला आपसी अविश्वास और राजनीतिक संघर्ष है। इन दो बड़े सदस्यों के बीच के विवादों ने अक्सर क्षेत्रीय सहयोग के प्रयासों को बाधित किया है। जब भी द्विपक्षीय तनाव बढ़ता है, तो सार्क की बैठकें और शिखर सम्मेलन प्रभावित होते हैं। इसके कारण आर्थिक एकीकरण और साझा विकास की योजनाएं प्रभावी ढंग से लागू नहीं हो पाती हैं। राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी संगठन की विफलता का मुख्य कारण बनी हुई है। यह दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग की संभावनाओं को सीमित करने वाली एक स्थाई चुनौती है। क्षेत्रीय विकास के लिए इन द्विपक्षीय मतभेदों को दूर करना अनिवार्य है।

104. (C) चीन
चीन सार्क का पूर्ण सदस्य नहीं है, बल्कि इसे पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। सार्क के पूर्ण सदस्यों में केवल दक्षिण एशियाई राष्ट्र शामिल हैं। चीन इस क्षेत्र के बाहर की एक बड़ी शक्ति है और इसकी भूमिका केवल चर्चाओं में भाग लेने और सहयोग के क्षेत्रों की पहचान करने तक सीमित है। यद्यपि कई सदस्य देशों ने चीन की पूर्ण सदस्यता का समर्थन किया है, लेकिन रणनीतिक कारणों से अभी तक इस पर कोई सहमति नहीं बनी है। अन्य विकल्प सार्क के संस्थापक और पूर्ण सदस्य राष्ट्र हैं। यह दक्षिण एशिया की क्षेत्रीय सीमाओं और कूटनीतिक पहचान को स्पष्ट करता है। चीन की भूमिका क्षेत्र में बढ़ती आर्थिक और रणनीतिक गतिविधियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण है।

105. (A) बहुराष्ट्रीय तेल कंपनियों ("सेवन सिस्टर्स") की शक्ति का मुकाबला करना।
ओपेक के गठन का मुख्य उद्देश्य तेल उत्पादक देशों के अपने संसाधनों पर नियंत्रण को मजबूत करना था। उस समय विश्व तेल बाजार पर कुछ शक्तिशाली पश्चिमी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का आधिपत्य था, जिन्हें "सेवन सिस्टर्स" कहा जाता था। ये कंपनियां तेल की कीमतें और उत्पादन निर्धारित करती थीं, जिससे उत्पादक राष्ट्रों को बहुत कम लाभ मिलता था। ओपेक ने इन देशों को एकजुट किया ताकि वे अपनी सामूहिक आवाज से तेल की कीमतों को प्रभावित कर सकें और अपने राष्ट्रीय

Downloaded from www.pdf.tube

76. (C) यूरोपीय संघ सहित औद्योगिक और विकासशील देशों दोनों का।
जी-20 एक व्यापक और प्रतिनिधि मंच है जो दुनिया की सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाता है। इसमें अमेरिका और ब्रिटेन जैसे विकसित देशों के साथ-साथ भारत और चीन जैसी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, यूरोपीय संघ भी इसमें एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में अपनी भूमिका निभाता है। यह विविधता जी-20 को वैश्विक आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करने और प्रभावी समाधान खोजने के लिए एक अत्यंत संतुलित और शक्तिशाली अंतरराष्ट्रीय मंच बनाने में सहायता प्रदान करती है। यह वैश्विक आर्थिक शासन में समावेशिता और प्रभावी नीतिगत समन्वय सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण और अनिवार्य माध्यम है।

77. (C) दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (SAFTA)।
दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना सार्क के इतिहास की एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य दक्षिण एशियाई देशों के बीच व्यापारिक बाधाओं और टैरिफ को कम करके आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है। यह समझौता क्षेत्र में एक साझा बाजार विकसित करने की दिशा में एक साहसिक प्रयास था। यद्यपि इसके पूर्ण कार्यान्वयन में राजनीतिक चुनौतियां रही हैं, लेकिन यह क्षेत्रीय एकीकरण और आर्थिक विकास की दिशा में सार्क की एक सकारात्मक और दीर्घकालिक पहल को दर्शाता है। यह दक्षिण एशिया के आर्थिक उत्थान और सदस्य देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को सुदृढ़ करने का आधार प्रदान करता है।

78. (C) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
ओपेक का मुख्यालय वास्तव में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में स्थित है, जो इस संगठन की प्रशासनिक गतिविधियों का केंद्र है। हालांकि, ऑस्ट्रिया स्वयं ओपेक का सदस्य नहीं है क्योंकि यह एक तेल निर्यातक देश नहीं है। ओपेक में केवल वे देश शामिल हैं जिनके पास बड़े तेल भंडार हैं और जो इसके निर्यात पर निर्भर हैं। मुख्यालय के लिए वियना का चयन इसकी तटस्थ स्थिति और अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका के कारण एक रणनीतिक निर्णय के रूप में किया गया था। यह संगठन के सुचारू संचालन और वैश्विक तेल नीतियों के प्रभावी प्रबंधन के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु सिद्ध हुआ है।

79. (B) ओएएस (OAS)
अमेरिकी राज्यों के संगठन की स्थापना 1948 में हुई थी, जो इसे दुनिया के सबसे पुराने क्षेत्रीय संगठनों में से एक बनाती है। इसका गठन पश्चिमी गोलार्ध के देशों के बीच शांति, न्याय और एकजुटता को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। इसके विपरीत, ओपेक, आसियान और सार्क की स्थापना इसके काफी समय बाद हुई थी। ओएएस का लंबा इतिहास क्षेत्रीय सहयोग और लोकतंत्र की रक्षा के लिए इसके निरंतर प्रयासों को दर्शाता है। यह संगठन आज भी अमेरिकी महाद्वीप की राजनीति में प्रासंगिक है और सदस्य देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करने का कार्य करता है। यह क्षेत्रीय अखंडता और लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण संस्था है।

80. (A) आम सहमति (Consensus)
विश्व व्यापार संगठन में निर्णय लेने की प्राथमिक पद्धति आम सहमति है, जिसका अर्थ है कि किसी भी निर्णय पर किसी सदस्य ने आधिकारिक आपत्ति न की हो। यह प्रणाली सुनिश्चित करती है कि व्यापारिक नियमों में सभी देशों की राय शामिल हो और कोई भी निर्णय उन पर थोपा न जाए। यद्यपि यह प्रक्रिया कभी-कभी धीमी हो सकती है, परंतु यह संगठन के भीतर लोकतांत्रिक समावेशिता और व्यापक स्वीकृति को बढ़ावा देती है। यह बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली में विश्वास बनाए रखने के लिए एक अनिवार्य और निष्पक्ष प्रक्रिया मानी जाती है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी सदस्यों के हितों को व्यापारिक नीतियों में उचित महत्व मिले।

81. (B) अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना।
संयुक्त राष्ट्र की एक बड़ी आलोचना यह है कि यह शक्तिशाली देशों द्वारा की जाने वाली एकपक्षीय सैन्य कार्रवाइयों को रोकने में विफल रहा है। जब महाशक्ति राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय नियमों की उपेक्षा करते हैं, तो संयुक्त राष्ट्र का प्राथमिक उद्देश्य, जो युद्धों को रोकना है, काफी दुर्बल हो जाता है। यह विफलता संगठन की प्रभावशीलता और निष्पक्षता पर गंभीर प्रश्न खड़े करती है। शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी केवल छोटे देशों तक सीमित नहीं होनी चाहिए। अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की विश्वसनीयता शक्तिशाली राज्यों की जवाबदेही पर निर्भर करती है। यह वैश्विक शासन प्रणाली में समानता और न्याय सुनिश्चित करने के लिए एक अनिवार्य चुनौती है।

82. (B) बुतरोस बुतरोस-घाली
'एजेंडा फॉर पीस' रिपोर्ट 1992 में पूर्व महासचिव बुतरोस बुतरोस-घाली द्वारा प्रस्तुत की गई थी। यह दस्तावेज शीत युद्ध के बाद की दुनिया में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका को पुनर्परिभाषित करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास था। इसमें कूटनीति, शांति स्थापना और शांति निर्माण की अवधारणाओं पर विस्तार से प्रकाश डाला गया था। रिपोर्ट ने वैश्विक संघर्षों को सुलझाने के लिए संगठन की क्षमताओं को मजबूत करने के कई सुझाव दिए थे। इसने समकालीन शांति अभियानों के लिए एक नया और प्रभावी रणनीतिक ढांचा तैयार किया। यह अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की दिशा में संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों को नई दिशा प्रदान करने वाला एक ऐतिहासिक दस्तावेज सिद्ध हुआ।

83. (C) A सही है लेकिन R गलत है।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार की मांग निरंतर की जा रही है क्योंकि इसका वर्तमान ढांचा 21वीं सदी की बदलती दुनिया को नहीं दर्शाता है। स्थाई सदस्यों की संख्या और उनकी वीटो शक्ति द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की पुरानी व्यवस्था पर आधारित है। भारत और ब्राजील जैसे उभरते हुए राष्ट्रों का मानना है कि परिषद में अधिक प्रतिनिधित्व होना चाहिए। यह कहना गलत है कि वर्तमान संरचना आज की वास्तविकताओं को दर्शाता है। इसके विपरीत, यह एक कालदोषयुक्त संरचना है जिसमें तत्काल सुधार की आवश्यकता है। यह संगठन की

NODIA

आधुनिक और व्यापक मार्गदर्शिका है। यह वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए एक एकीकृत और प्रभावी रणनीति प्रस्तुत करता है। यह अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के साथ-साथ मानवीय कल्याण और पर्यावरणीय स्थिरता के बीच के गहरे संबंधों को स्पष्ट रूप से उजागर करता है।

127. (D) सुरक्षा परिषद की संरचना और शक्तियां।
संयुक्त राष्ट्र चार्टर संशोधन की बहसों में सबसे जटिल मुद्दा सुरक्षा परिषद का पुनर्गठन है। इसमें स्थाई सदस्यों की संख्या बढ़ाना, वीटो शक्ति की समीक्षा करना और दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों को उचित प्रतिनिधित्व देना शामिल है। कई राष्ट्र मानते हैं कि वर्तमान ढांचा अलोकतांत्रिक है और इसे आज की भू-राजनीतिक वास्तविकताओं के अनुरूप होना चाहिए। इस मुद्दे पर स्थाई सदस्यों और अन्य राष्ट्रों के बीच गहरे मतभेद हैं। यह विवाद संगठन की भविष्य की प्रासंगिकता और प्रभावशीलता के लिए अत्यंत निर्णायक माना जाता है। यह अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में शक्ति संतुलन और लोकतांत्रिक सुधारों की राह में एक महत्वपूर्ण चुनौती है। सुरक्षा परिषद में सुधार के बिना संयुक्त राष्ट्र की लोकतांत्रिक वैधता और उसकी वैश्विक स्वीकार्यता पर निरंतर प्रश्नचिह्न लगे रहते हैं।

128. (B) ब्राजील, जर्मनी और जापान
भारत ने ब्राजील, जर्मनी और जापान के साथ मिलकर जी-4 समूह बनाया है, जो सुरक्षा परिषद में स्थाई सदस्यता के लिए एक-दूसरे के दावों का समर्थन करते हैं। ये देश अपनी आर्थिक शक्ति और वैश्विक प्रभाव के आधार पर परिषद के विस्तार की मांग कर रहे हैं। उनका तर्क है कि परिषद को अधिक लोकतांत्रिक और प्रतिनिधि बनाने के लिए इन प्रमुख राष्ट्रों का इसमें शामिल होना आवश्यक है। जी-4 का सामूहिक प्रयास संयुक्त राष्ट्र के ढांचे में सुधार के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निरंतर दबाव बनाए रखने का एक प्रमुख साधन है। यह वर्तमान वैश्विक वास्तविकताओं और उभरती हुई शक्तियों की उपेक्षा को दूर करने का एक संगठित कूटनीतिक प्रयास है। यह सुरक्षा परिषद को अधिक समावेशी और प्रभावी बनाने की दिशा में भारत की अडिग प्रतिबद्धता और रणनीतिक कूटनीति का प्रमाण है।

129. (C) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
गुजराल सिद्धांत ने यह क्रांतिकारी प्रस्ताव दिया कि भारत को अपने छोटे पड़ोसियों के साथ संबंधों में पारस्परिकता नहीं मांगनी चाहिए। इसका उद्देश्य विश्वास निर्माण और क्षेत्रीय सद्भावना को बढ़ावा देना था। हालांकि, यह सिद्धांत सभी पड़ोसियों पर सार्वभौमिक रूप से लागू नहीं था; यह मुख्य रूप से नेपाल, भूटान और बांग्लादेश जैसे छोटे राष्ट्रों के लिए था। पाकिस्तान और चीन जैसे बड़े देशों के साथ संबंधों में सुरक्षा चिंताओं और पारस्परिकता का महत्व बना रहा। अतः, यह नीति क्षेत्रीय कूटनीति का एक विशिष्ट उपकरण थी जो भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंधों में एक नया और उदार दृष्टिकोण प्रस्तुत करती थी। इसने दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग की संभावनाओं को सुदृढ़ करने और अविश्वास को कम करने में एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक भूमिका निभाई।

130. (B) गठबंधनों से बंधे बिना राष्ट्रीय हित के आधार पर विदेश नीति के निर्णय लेना।
समकालीन भारतीय विदेश नीति में "रणनीतिक स्वायत्तता" का अर्थ है कि भारत अपनी नीतियों को किसी बाहरी दबाव या गठबंधन के अधीन नहीं होने देता। यह भारत को विभिन्न वैश्विक शक्तियों के साथ स्वतंत्र रूप से जुड़ने और अपने हितों के अनुसार निर्णय लेने की सुविधा प्रदान करता है। इसका उद्देश्य एक बहुध्रुवीय दुनिया में भारत के प्रभाव को बढ़ाना और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यह दृष्टिकोण भारत को अंतरराष्ट्रीय मंच पर एक स्वतंत्र और विश्वसनीय शक्ति के रूप में कार्य करने की क्षमता प्रदान करता है। यह राष्ट्रीय संप्रभुता और वैश्विक शांति के प्रति भारत की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करता है। यह नीति की गतिशीलता और बदलती वैश्विक परिस्थितियों के अनुरूप भारत की कूटनीतिक स्वाधीनता और उसके वैश्विक लक्ष्यों की प्राप्ति का एक अनिवार्य और प्रभावी आधार है।

131. (B) विकासशील और अल्पविकसित देश।
उत्तर-दक्षिण संवाद के संदर्भ में 'दक्षिण' शब्द दुनिया के उन राष्ट्रों को संदर्भित करता है जो आर्थिक रूप से विकासशील या अल्पविकसित हैं। ये देश मुख्य रूप से एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में स्थित हैं। 'दक्षिण' के देशों की साझा चुनौतियां गरीबी, औद्योगिक पिछड़ेपन और वैश्विक व्यापार प्रणाली में असमानता से संबंधित हैं। ये राष्ट्र मिलकर एक अधिक न्यायपूर्ण अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की मांग करते हैं। यह वर्गीकरण केवल भौगोलिक नहीं, बल्कि आर्थिक और विकास के स्तर पर आधारित एक राजनीतिक पहचान है। यह वैश्विक सहयोग में विकासशील राष्ट्रों की एकजुटता और उनके सामूहिक संघर्ष को दर्शाता है। यह अंतरराष्ट्रीय आर्थिक शासन में समानता और न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में विकासशील देशों की साझा आकांक्षाओं और उनके संगठित प्रयासों का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है।

132. (A) नव-उपनिवेशवाद (Neo-colonialism)
क्वामे न्क्रूमा ने नव-उपनिवेशवाद की अवधारणा को दृढ़ता से प्रतिपादित किया था, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे विकसित देश पूर्व उपनिवेशों पर अपना आर्थिक नियंत्रण बनाए रखते हैं। उनके अनुसार, राजनीतिक स्वतंत्रता के बावजूद ये देश अपनी आर्थिक नीतियों के लिए बाहरी शक्तियों पर निर्भर रहते हैं। न्क्रूमा ने चेतावनी दी थी कि यह अप्रत्यक्ष प्रभुत्व वास्तविक स्वतंत्रता के लिए एक बड़ा खतरा है। उनके विचारों ने विकासशील देशों के बीच अपनी संप्रभुता की रक्षा करने और सामूहिक आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए एक नई चेतना जागृत की थी। यह अवधारणा आधुनिक समय में शोषण के सूक्ष्म रूपों को समझने और राष्ट्रों की संप्रभुता के प्रति जागरूक रहने के लिए अनिवार्य है। यह स्वतंत्र राष्ट्रों के आर्थिक और राजनीतिक स्वावलंबन के संघर्ष को ऐतिहासिक और सैद्धांतिक संदर्भ प्रदान करता है।

133. (B) केवल 2 और 3
निर्भरता सिद्धांत यह स्पष्ट करता है कि विकसित राष्ट्रों की प्रगति अक्सर विकासशील राष्ट्रों के संसाधनों के शोषण पर

Click Here to Buy book on Amazon

विचार उत्पन्न करने में सहायता करती है। जब सरकारी स्तर पर बातचीत बंद या कठिन हो जाती है, तब यह संवाद संबंधों को सुधारने के लिए एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करता है। यह औपचारिक कूटनीति के लिए एक सहायक और महत्वपूर्ण उपकरण माना जाता है। यह राष्ट्रों के बीच आपसी समझ बढ़ाने और संघर्षों के दीर्घकालिक समाधान खोजने की दिशा में एक प्रभावी और सकारात्मक पहल है।

92. (B) 1971 का युद्ध और बांग्लादेश का निर्माण
शिमला समझौता 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, जो 1971 के ऐतिहासिक युद्ध की समाप्ति के बाद संपन्न हुआ। इस युद्ध के परिणामस्वरूप बांग्लादेश का उदय हुआ और दक्षिण एशिया की भू-राजनीति पूरी तरह बदल गई। समझौते का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच भविष्य के संबंधों को शांतिपूर्ण और द्विपक्षीय आधार पर पुनर्स्थापित करना था। इसने यह सिद्धांत स्थापित किया कि सभी विवादों को बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के केवल बातचीत के माध्यम से ही हल किया जाना चाहिए। यह समझौता दक्षिण एशियाई क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक दस्तावेज सिद्ध हुआ है। यह द्विपक्षीय संबंधों में विश्वास बहाल करने का एक गंभीर प्रयास था।

93. (A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
भारत ने लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक स्थाई सीट के लिए अपना मजबूत दावा प्रस्तुत किया है। यह दावा भारत की विशाल जनसंख्या, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र होने और बढ़ती आर्थिक शक्ति पर आधारित है। इसके अतिरिक्त, भारत संयुक्त राष्ट्र के शांति स्थापना अभियानों में दुनिया के सबसे बड़े सैन्य योगदानकर्ताओं में से एक रहा है। इन सभी कारकों के कारण, भारत का मानना है कि उसे वैश्विक निर्णय लेने की प्रक्रिया में एक उचित और प्रभावी स्थान प्राप्त होना चाहिए। सुरक्षा परिषद में भारत की उपस्थिति अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के प्रयासों को अधिक समावेशी और लोकतांत्रिक बनाएगी। यह वर्तमान वैश्विक वास्तविकताओं के अनुरूप सुधार है।

94. (C) विश्व अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक रूप से वंचित और शोषित हैं।
निर्भरता सिद्धांत के अनुसार 'परिधि' उन विकासशील और अल्पविकसित राष्ट्रों को संदर्भित करती है जिनकी अर्थव्यवस्थाएं विकसित देशों पर निर्भर हैं। ये राष्ट्र वैश्विक व्यापार प्रणाली में एक अधीनस्थ भूमिका निभाते हैं और मुख्य रूप से कच्चे माल के निर्यातक के रूप में कार्य करते हैं। संरचनात्मक रूप से, इन देशों को वैश्विक पूंजीवादी व्यवस्था द्वारा इस प्रकार वंचित रखा जाता है कि उनकी प्रगति केंद्र के देशों के लाभ के लिए उपयोग होती है। यह स्थिति इन राष्ट्रों में स्थाई गरीबी और आर्थिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण मानी जाती है। यह सिद्धांत वैश्विक स्तर पर धन और शक्ति के असमान वितरण के ऐतिहासिक और संरचनात्मक कारणों का गहराई से विश्लेषण करता है।

95. (B) P-3, Q-1, R-4, S-2
अंतरराष्ट्रीय संबंधों की अवधारणाएं विभिन्न ऐतिहासिक संदर्भों और विद्वानों से जुड़ी हुई हैं। नव-उपनिवेशवाद का विचार क्वामे न्क्रूमा द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था। उत्तर-दक्षिण संवाद के मुद्दों को ब्रांट रिपोर्ट ने प्रमुखता से वैश्विक मंच पर उठाया। दक्षिण-दक्षिण सहयोग बांडुंग सम्मेलन की भावना और विकासशील देशों की एकजुटता का प्रतिबिंब है। विश्व व्यापार संगठन के सिद्धांतों में 'सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र' का विचार एक अनिवार्य आधार है। ये सभी तत्व वैश्विक शासन और आर्थिक न्याय की दिशा में किए गए प्रयासों को रेखांकित करते हैं। ये अवधारणाएं राष्ट्रों के बीच संबंधों और वैश्विक आर्थिक शासन के बदलते स्वरूप को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण आधार प्रदान करती हैं।

96. (B) सब कुछ एक ही पैकेज का हिस्सा है और जब तक सब कुछ तय नहीं हो जाता तब तक कुछ भी तय नहीं माना जाता।
डब्ल्यूटीओ वार्ताओं में "सिंगल अंडरटेकिंग" का सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि सदस्य देश केवल उन्हीं समझौतों को नहीं चुन सकते जो उनके अनुकूल हों। इसके बजाय, पूरे वार्ता पैकेज को एक साथ स्वीकार करना अनिवार्य होता है। यह व्यवस्था विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि, सेवाओं और बौद्धिक संपदा के बीच संतुलन बनाने में मदद करती है। इसका उद्देश्य यह है कि कोई भी मुद्दा तब तक अंतिम रूप से तय नहीं माना जाएगा जब तक कि सभी विषयों पर पूर्ण सहमति न बन जाए। यह बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली में व्यापक समझौतों और निष्पक्षता को सुनिश्चित करने का एक प्रभावी तंत्र है। यह सभी सदस्य राष्ट्रों के हितों के बीच एक आवश्यक तालमेल बनाने का प्रयास करता है।

97. (B) विकासशील देशों का।
जी-77 विकासशील देशों का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना सामूहिक आर्थिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए की गई थी। यह समूह संयुक्त राष्ट्र और अन्य मंचों पर विकासशील राष्ट्रों की बातचीत की शक्ति को मजबूत करता है। इसकी सदस्यता में लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के राष्ट्र शामिल हैं जो एक न्यायपूर्ण वैश्विक आर्थिक व्यवस्था की मांग करते हैं। यद्यपि वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 77 से कहीं अधिक है, लेकिन यह नाम विकासशील देशों की ऐतिहासिक एकजुटता के प्रतीक के रूप में आज भी बना हुआ है। यह समूह अंतरराष्ट्रीय आर्थिक शासन में विकासशील देशों के अधिकारों और उनकी न्यायसंगत भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और सक्रिय वैश्विक मंच है।

98. (A) केवल 1
नव-उपनिवेशवाद यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि औपचारिक राजनीतिक स्वतंत्रता के बावजूद कई पूर्व उपनिवेश अभी भी आर्थिक रूप से शक्तिशाली राष्ट्रों के अधीन हैं। डब्ल्यूटीओ का वास्तविक उद्देश्य व्यापारिक बाधाओं को कम करना है, न कि संरक्षणवाद को बढ़ावा देना। वहीं, एनआईईओ का लक्ष्य मौजूदा ब्रेटन वुड्स प्रणाली में सुधार करना और उसे विकासशील देशों के लिए अधिक न्यायसंगत बनाना था, न कि

Downloaded from www.pdf.tube

वैश्विक प्रासंगिकता और लोकतांत्रिक वैधता को सुदृढ़ करने के लिए अनिवार्य है।

84. (D) प्रशासनिक शाखा
सचिवालय संयुक्त राष्ट्र का मुख्य प्रशासनिक अंग है जो संगठन के दैनिक कार्यों के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है। इसका नेतृत्व महासचिव करते हैं, जो संयुक्त राष्ट्र के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। सचिवालय विभिन्न अंगों द्वारा लिए गए निर्णयों और नीतियों को लागू करने का कार्य करता है। इसमें दुनिया भर के हजारों अंतरराष्ट्रीय कर्मचारी शामिल होते हैं जो शांति अभियानों, मानवीय सहायता और सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षणों का संचालन करते हैं। यह अंग संगठन के सुचारू संचालन के लिए एक रीढ़ की हड्डी के समान है। यह वैश्विक सहयोग और अंतरराष्ट्रीय प्रशासन के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने वाला एक अनिवार्य स्तंभ है।

85. (B) गुटनिरपेक्ष विदेश नीति।
स्वतंत्रता के बाद भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई, जिसने इसे महाशक्तियों के सैन्य गुटों से स्वतंत्र रखा। इस नीति ने भारत को एशिया और अफ्रीका के नए स्वतंत्र देशों के नेता के रूप में उभरने में सहायता प्रदान की। भारत ने इन राष्ट्रों की आवाज बनकर अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का पुरजोर विरोध किया। यह दृष्टिकोण न केवल भारत के स्वाभिमान का प्रतीक था, बल्कि इसने विकासशील देशों को एक नया विकल्प भी प्रदान किया। इसने वैश्विक राजनीति में भारत के नैतिक प्रभाव को सुदृढ़ किया और उसे एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में स्थापित किया। यह भारत की रणनीतिक स्वायत्तता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था।

86. (B) श्रीलंकाई जातीय संघर्ष में इसका हस्तक्षेप जिसके कारण 1987 का भारत-श्रीलंका समझौता हुआ।
श्रीलंका के जातीय संघर्ष में भारत का हस्तक्षेप पड़ोसी देशों के विवादों को सुलझाने के उसके प्रयासों का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। 1987 के समझौते का उद्देश्य श्रीलंका की एकता को बनाए रखते हुए तमिल अल्पसंख्यकों की मांगों को पूरा करना था। इसके तहत भारत ने शांति बनाए रखने के लिए अपनी सेना भी भेजी थी। यद्यपि इस हस्तक्षेप के परिणाम मिश्रित रहे, लेकिन यह क्षेत्रीय स्थिरता के प्रति भारत की सक्रियता को दर्शाता है। यह घटना भारत की मध्यस्थता और क्षेत्रीय सुरक्षा चिंताओं के जटिल संबंधों को स्पष्ट करती है। यह पड़ोसी राष्ट्रों के साथ शांति स्थापना के लिए भारत की गंभीर प्रतिबद्धता का एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक ऐतिहासिक उदाहरण है।

87. (C) 1971 की भारत-सोवियत शांति, मित्रता और सहयोग संधि
1971 की भारत-सोवियत संधि भारत के सामरिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। इस संधि ने बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के कठिन समय में भारत को एक शक्तिशाली मित्र का सुरक्षा आश्वासन प्रदान किया। यद्यपि भारत गुटनिरपेक्ष था, परंतु इस समझौते ने देश के सामने खड़े तत्कालीन सुरक्षा खतरों को टालने में मदद की। इसने क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को भारत के पक्ष में बनाए रखने में एक निर्णायक भूमिका निभाई। यह संधि भारत की दूरदर्शी कूटनीति और अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने की दृढ़ इच्छाशक्ति का एक उत्कृष्ट प्रमाण है। यह अंतरराष्ट्रीय संबंधों में रणनीतिक साझेदारी और राष्ट्रीय हितों के सफल समन्वय को स्पष्ट रूप से उजागर करता है।

88. (A) सैन्य गठबंधनों की प्रणाली के प्रति प्रतिबद्धता।
भारतीय विदेश नीति कभी भी सैन्य गठबंधनों के पक्ष में नहीं रही है और इसने सदैव किसी भी शक्ति गुट का हिस्सा बनने से इनकार किया है। इसके स्थान पर, भारत ने रणनीतिक स्वायत्तता, संप्रभुता के सम्मान और एक न्यायपूर्ण विश्व व्यवस्था के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया है। भारत का विश्वास अंतरराष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान और अहस्तक्षेप के सिद्धांतों में रहा है। सैन्य गुटों से दूरी बनाए रखना भारत को वैश्विक स्तर पर एक स्वतंत्र और विश्वसनीय शक्ति के रूप में कार्य करने की अनुमति देता है। यह राष्ट्रीय संप्रभुता और वैश्विक शांति के प्रति भारत की दीर्घकालिक और सुदृढ़ प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करने वाला एक आधारभूत सिद्धांत है।

89. (C) पड़ोसी पहले नीति (Neighbourhood First Policy)
'पड़ोसी पहले' नीति भारत की विदेश नीति का एक सक्रिय ढांचा है जो दक्षिण एशियाई पड़ोसियों के साथ संबंधों को प्राथमिकता देता है। इसका उद्देश्य कनेक्टिविटी, व्यापार और आपसी विश्वास को बढ़ाकर क्षेत्र में साझा समृद्धि सुनिश्चित करना है। भारत अपने पड़ोसियों के विकास और सुरक्षा में एक विश्वसनीय भागीदार की भूमिका निभाता है। यह नीति इस मान्यता पर आधारित है कि एक स्थिर और खुशहाल पड़ोस भारत की अपनी प्रगति के लिए अनिवार्य है। इसके माध्यम से भारत क्षेत्रीय सहयोग को सुदृढ़ करने का निरंतर प्रयास करता है। यह दक्षिण एशियाई देशों के बीच आपसी सहयोग और सौहार्दपूर्ण संबंधों को नया आयाम प्रदान करने का एक प्रभावी माध्यम है।

90. (A) 1, 4, 2, 3
भारतीय विदेश नीति की प्रमुख घटनाओं का कालक्रम देश के कूटनीतिक विकास को दर्शाता है। पंचशील समझौते पर 1954 में हस्ताक्षर किए गए थे। इसके पश्चात 1972 में पाकिस्तान के साथ शिमला समझौता हुआ। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 1974 में पोखरण में किया था। अंत में, 1990 के दशक की शुरुआत में 'लुक ईस्ट' नीति को दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ आर्थिक संबंधों को बढ़ाने के लिए आरंभ किया गया था। यह विकास क्रम भारत की बदलती राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और वैश्विक भूमिका को स्पष्ट रूप से उजागर करता है। यह दर्शाता है कि कैसे भारत ने बदलती वैश्विक परिस्थितियों के अनुरूप अपनी विदेश नीति को सफलतापूर्वक ढाला और विस्तार प्रदान किया है।

91. (C) शिक्षाविदों और सेवानिवृत्त अधिकारियों जैसे गैर-सरकारी अभिनेताओं के बीच अनौपचारिक संवाद।
"ट्रैक-टू कूटनीति" विवादों को सुलझाने और विश्वास निर्माण के लिए एक अनौपचारिक और गैर-सरकारी माध्यम है। इसमें शामिल व्यक्ति आधिकारिक प्रतिनिधि नहीं होते, जिससे वे अधिक खुलकर और रचनात्मक ढंग से चर्चा कर सकते हैं। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से कठिन और संवेदनशील मुद्दों पर नए

NODIA

हितों की रक्षा कर सकें। यह प्राकृतिक संसाधनों पर संप्रभुता प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इसने वैश्विक ऊर्जा राजनीति में विकासशील देशों की शक्ति को सुदृढ़ किया।

106. (B) संयुक्त राष्ट्र
संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार, संगठन अपने सभी सदस्य देशों की संप्रभु समानता के सिद्धांत पर आधारित है। इसका अर्थ है कि प्रत्येक देश, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, धनी हो या निर्धन, अंतरराष्ट्रीय कानून के समक्ष समान अधिकार रखता है। यह सिद्धांत महासभा में 'एक देश, एक वोट' की व्यवस्था के माध्यम से परिलक्षित होता है। यद्यपि सुरक्षा परिषद में शक्ति का वितरण असमान है, परंतु संप्रभु समानता संयुक्त राष्ट्र की संरचना और उसकी कार्यप्रणाली का एक अनिवार्य और पवित्र आधार माना जाता है। यह अंतरराष्ट्रीय संबंधों में निष्पक्षता और लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। यह वैश्विक शांति के लिए राष्ट्रों के बीच परस्पर सम्मान सुनिश्चित करता है।

107. (D) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।
अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का प्राथमिक कार्य राज्यों के बीच के कानूनी विवादों को सुलझाना है और यह केवल देशों से संबंधित मामलों की सुनवाई करता है। यह व्यक्तियों पर युद्ध अपराधों के लिए मुकदमा नहीं चला सकता, क्योंकि इसके लिए अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय जैसी अलग संस्थाएं मौजूद हैं। आईसीजे संयुक्त राष्ट्र का मुख्य न्यायिक अंग है जो अंतरराष्ट्रीय कानूनों और संधियों की व्याख्या करता है। यह राज्यों द्वारा प्रस्तुत मामलों पर अपने निर्णय देता है और संयुक्त राष्ट्र के अन्य अंगों को परामर्शदात्री राय भी प्रदान करता है। यह अंतरराष्ट्रीय कानून के शासन को बनाए रखने और न्याय सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह वैश्विक न्याय व्यवस्था का एक अनिवार्य स्तंभ है।

108. (C) सुरक्षा परिषद को सैन्य बल सहित प्रवर्तन कार्रवाई करने के लिए अधिकृत करता है।
संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अध्याय सात सुरक्षा परिषद को अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बहाल करने के लिए व्यापक शक्तियां प्रदान करता है। इसके तहत, यदि कोई देश विश्व शांति के लिए खतरा पैदा करता है, तो परिषद उस पर प्रतिबंध लगा सकती है या सैन्य कार्रवाई का आदेश दे सकती है। यह अध्याय संयुक्त राष्ट्र को अपने उद्देश्यों को लागू करने के लिए एक अनिवार्य और शक्तिशाली कानूनी आधार प्रदान करता है। यह संगठन की उन प्रवर्तन शक्तियों का केंद्र है जो इसे मात्र एक चर्चा मंच से ऊपर उठाती हैं। यह अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में आक्रामकता को रोकने और शांति बनाए रखने का एक प्रभावी माध्यम है। यह सुरक्षा परिषद की निर्णायक और महत्वपूर्ण वैश्विक भूमिका को स्पष्ट करता है।

109. (B) राज्यों द्वारा गठबंधनों के माध्यम से राष्ट्रीय लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र मंच का उपयोग।
संयुक्त राष्ट्र के भीतर कूटनीति का अर्थ है कि राष्ट्र अपने हितों की पूर्ति के लिए इस वैश्विक मंच का रणनीतिक उपयोग करते हैं। विभिन्न देश समान विचारधारा वाले राष्ट्रों के साथ गठबंधन बनाकर प्रस्तावों पर मतदान और वार्ताओं को प्रभावित करते हैं। यह प्रक्रिया दर्शाती है कि संयुक्त राष्ट्र केवल एक तटस्थ संस्था नहीं है, बल्कि यह अंतरराष्ट्रीय राजनीति और शक्ति संघर्ष का एक जीवंत मैदान है। यहाँ राष्ट्र अपनी 'मृदु शक्ति' और कूटनीतिक कौशल के माध्यम से वैश्विक मानदंडों और नीतियों को दिशा देने का प्रयास करते हैं। यह बहुपक्षीय कूटनीति का एक अनिवार्य हिस्सा है जहाँ राष्ट्रहित और वैश्विक लक्ष्यों के बीच संतुलन बनाने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है।

110. (B) G4 राष्ट्र (ब्राजील, जर्मनी, भारत, जापान)
जी-4 उन चार देशों का समूह है जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थाई सदस्य बनने के लिए एक-दूसरे के दावों का समर्थन करते हैं। इनमें ब्राजील, जर्मनी, भारत और जापान शामिल हैं, जो वैश्विक राजनीति में अपनी बढ़ती भूमिका के आधार पर सुधार की मांग कर रहे हैं। इन राष्ट्रों का मानना है कि वर्तमान परिषद में लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के बड़े लोकतंत्रों का अभाव है। उनका यह प्रस्ताव परिषद को अधिक प्रतिनिधि और प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक प्रयास माना जाता है। यह सुरक्षा परिषद के ढांचे में लोकतांत्रिक सुधार और वर्तमान वैश्विक वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करने की दिशा में एक सशक्त पहल है।

111. (C) महासभा
संयुक्त राष्ट्र के मुख्य बजट की समीक्षा और उसे अनुमोदित करने की अंतिम शक्ति महासभा के पास होती है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि संगठन के वित्तीय खर्चों पर सभी सदस्य देशों का नियंत्रण रहे। महासभा का पांचवां भाग विशेष रूप से बजट और प्रशासनिक मामलों पर चर्चा करता है। बजट का अनुमोदन संगठन के विभिन्न कार्यक्रमों और अभियानों के सुचारू संचालन के लिए अनिवार्य है। यह महासभा की उन शक्तियों में से एक है जो इसे संयुक्त राष्ट्र के प्रशासन में एक निर्णायक भूमिका प्रदान करती है। यह संगठन की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। यह संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य राष्ट्रों की समान भागीदारी और वित्तीय जिम्मेदारी को रेखांकित करता है।

112. (C) सुरक्षा परिषद के पांच स्थाई सदस्य।
"पी-5" शब्द सुरक्षा परिषद के उन पांच शक्तिशाली राष्ट्रों को संदर्भित करता है जिनके पास वीटो शक्ति है। ये देश चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका हैं। उन्हें यह विशेष दर्जा द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद उनकी वैश्विक स्थिति के कारण दिया गया था। ये सदस्य परिषद के किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय को अकेले ही रोकने की क्षमता रखते हैं। संगठन के भीतर इनकी स्थाई उपस्थिति और विशेष अधिकार अक्सर अंतरराष्ट्रीय राजनीति में बहस और सुधार की मांगों का मुख्य केंद्र होते हैं। यह सुरक्षा परिषद के ढांचे में शक्ति के असंतुलन और ऐतिहासिक प्रभाव को दर्शाता है। यह अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रबंधन में महाशक्तियों की विशिष्ट भूमिका को स्पष्ट करता है।

Click Here to Buy book on Amazon

113. (C) केवल 1 और 3
भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन का एक संस्थापक सदस्य था, जिसने शीत युद्ध के दौरान किसी भी सैन्य गुट में शामिल न होने की नीति अपनाई थी। समकालीन समय में, भारत की 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' उसकी पुरानी 'लुक ईस्ट' नीति का अधिक सक्रिय और विस्तृत स्वरूप है। हालांकि, गुजराल सिद्धांत छोटे पड़ोसियों के साथ सख्त पारस्परिकता के स्थान पर उदारता और एकतरफा रियायतें देने पर बल देता है। यह भारतीय विदेश नीति के विकासवादी और अनुकूलन योग्य चरित्र को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है। यह राष्ट्रहित और क्षेत्रीय स्थिरता के बीच एक प्रभावी संतुलन बनाने का प्रयास है। यह भारत की रणनीतिक स्वायत्तता और पड़ोसी राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के प्रति उसकी निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

114. (B) गुटनिरपेक्ष आंदोलन
1955 में आयोजित बांडुंग सम्मेलन एशिया और अफ्रीका के नव स्वतंत्र देशों के बीच एकता और सहयोग का एक ऐतिहासिक मील का पत्थर था। इस सम्मेलन में शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व और उपनिवेशवाद के विरोध के सिद्धांतों पर चर्चा की गई, जिसने गुटनिरपेक्ष आंदोलन के गठन की आधारशिला रखी। इसने इन राष्ट्रों को अपनी स्वतंत्र पहचान बनाने और महाशक्तियों के दबाव से बचने के लिए एक साझा मंच प्रदान किया। बांडुंग की भावना आज भी विकासशील देशों के बीच दक्षिण-दक्षिण सहयोग की प्रेरणा बनी हुई है। यह वैश्विक राजनीति में विकासशील राष्ट्रों की सामूहिक आवाज और उनके स्वाभिमान का प्रतीक था। इसने अंतरराष्ट्रीय संबंधों में एक नए और न्यायपूर्ण वैश्विक दृष्टिकोण के उदय का मार्ग प्रशस्त किया।

115. (C) वैश्विक निशस्त्रीकरण और शस्त्र नियंत्रण।
भारत ने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर सदैव हथियारों की होड़ को समाप्त करने और पूर्ण परमाणु निशस्त्रीकरण का समर्थन किया है। भारतीय कूटनीति का यह विश्वास रहा है कि वैश्विक शांति के लिए हथियारों के भंडार को कम करना और सामूहिक सुरक्षा को बढ़ावा देना आवश्यक है। भारत ने निशस्त्रीकरण के लिए कई प्रस्ताव पेश किए हैं जो भेदभाव रहित और सार्वभौमिक होने चाहिए। यह प्रतिबद्धता भारत के एक शांतिप्रिय और जिम्मेदार राष्ट्र होने के आदर्शों को दर्शाती है, जो युद्ध के स्थान पर सहयोग को प्राथमिकता देता है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा और वैश्विक स्थिरता के बीच एक तार्किक समन्वय स्थापित करने का प्रयास है। भारत का यह रुख अंतरराष्ट्रीय संबंधों में नैतिक मूल्यों और शांति के प्रति उसकी अडिग निष्ठा का प्रमाण है।

116. (B) अंटार्कटिका में राजनीतिक स्थिति।
भारत की सुरक्षा चिंताएं मुख्य रूप से उसके निकटतम पड़ोस और हिंद महासागर क्षेत्र पर केंद्रित हैं। सीमा पार आतंकवाद, घुसपैठ और पड़ोसी देशों के साथ क्षेत्रीय विवाद भारत के लिए निरंतर बनी रहने वाली रणनीतिक चुनौतियां हैं। इसके अतिरिक्त, हिंद महासागर में समुद्री सुरक्षा और व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा भी भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अंटार्कटिका की राजनीतिक स्थिति, हालांकि वैज्ञानिक रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन यह भारत की प्राथमिक और तत्काल सुरक्षा चिंताओं में शामिल नहीं मानी जाती है। भारत की सुरक्षा नीति मुख्य रूप से उन खतरों पर केंद्रित है जो सीधे तौर पर उसकी क्षेत्रीय अखंडता और आंतरिक शांति को प्रभावित करते हैं। यह राष्ट्रीय हितों और रणनीतिक प्राथमिकताओं के तार्किक निर्धारण को स्पष्ट करता है।

NODIA

117. (C) सोवियत संघ (USSR) के साथ शांति, मित्रता और सहयोग की संधि।
1971 में सोवियत संघ के साथ हस्ताक्षरित संधि ने भारत को एक गंभीर सुरक्षा संकट के समय अत्यंत आवश्यक राजनयिक और सामरिक समर्थन प्रदान किया। यह संधि ऐसे समय में हुई थी जब अमेरिका और चीन पाकिस्तान के साथ खड़े थे। इसने भारत को बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए आत्मविश्वास और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा गारंटी दी। यह समझौता भारत की विदेश नीति में एक रणनीतिक बदलाव था, जिसने दक्षिण एशिया के इतिहास और भूगोल को स्थायी रूप से बदलने में मदद की। यह संधि भारत की दूरदर्शी कूटनीति और अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने की दृढ़ इच्छाशक्ति का एक उत्कृष्ट प्रमाण है। इसने क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को भारत के पक्ष में बनाए रखने में एक निर्णायक भूमिका निभाई।

118. (C) संवाद, बातचीत और विवादों का शांतिपूर्ण समाधान।
भारत की मध्यस्थ भूमिका सदैव इस विश्वास पर टिकी रही है कि संघर्षों का स्थाई समाधान केवल बातचीत और आपसी समझ के माध्यम से ही संभव है। भारत ने अंतरराष्ट्रीय विवादों में बल प्रयोग या बाहरी समाधान थोपने के बजाय हमेशा शांतिपूर्ण संवाद के मार्ग को प्रोत्साहित किया है। अपनी निष्पक्ष और स्वतंत्र स्थिति का उपयोग करते हुए, भारत ने अक्सर विभिन्न पक्षों के बीच एक सेतु का कार्य किया है। यह दृष्टिकोण भारतीय सभ्यता के अहिंसा और सहिष्णुता के मूल्यों को अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में प्रदर्शित करता है। यह वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए भारत की सकारात्मक और रचनात्मक भूमिका को सुदृढ़ करता है। यह अंतरराष्ट्रीय संबंधों में संवाद और सहयोग की महत्ता को रेखांकित करने वाली एक महत्वपूर्ण और प्रभावी कूटनीतिक रणनीति है।

119. (A) आर्थिक उदारीकरण और पश्चिम के साथ अधिक जुड़ाव की ओर कदम।
1990 के दशक की शुरुआत में भारत ने अपनी आर्थिक और विदेश नीति में एक व्यापक बदलाव किया, जिसे 'एलपीजी' सुधारों के रूप में जाना जाता है। शीत युद्ध की समाप्ति और सोवियत संघ के पतन के बाद, भारत ने पश्चिमी देशों के साथ अपने आर्थिक संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया। इस बदलाव का उद्देश्य वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत होना और विदेशी निवेश को आकर्षित करना था। इसने भारत को एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति के रूप में विश्व पटल पर स्थापित करने में मदद की। यह नीति की गतिशीलता और बदलती वैश्विक परिस्थितियों के अनुरूप भारत की कूटनीतिक और आर्थिक दिशा को नया विस्तार प्रदान करने का एक सफल प्रयास था। इसने भारत के वैश्विक प्रभाव और उसकी आर्थिक विकास की संभावनाओं को सुदृढ़ किया।

120. (C) A सही है लेकिन R गलत है।
नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था (NIEO) अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकी, क्योंकि विकसित देशों ने अपनी आर्थिक शक्ति को छोड़ने में कोई रुचि नहीं दिखाई। उत्तरी राष्ट्रों ने अक्सर इन मांगों का विरोध किया और व्यापारिक नियमों में बड़े बदलावों के प्रति अनिच्छा व्यक्त की। विकासशील देशों के पास विकसित देशों पर दबाव बनाने के लिए पर्याप्त संसाधनों और एकजुटता की भी कमी थी। अतः, राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी और हितों के टकराव ने इस पहल को काफी हद तक अप्रभावी बना दिया। यह वैश्विक आर्थिक शासन में सुधार की जटिलताओं और राष्ट्रों के बीच मौजूद गहरी असमानता को स्पष्ट रूप से उजागर करता है। यह अंतरराष्ट्रीय संबंधों में आर्थिक शक्ति और न्याय के बीच के निरंतर चलने वाले संघर्ष को दर्शाता है।

121. (B) डब्ल्यूटीओ (WTO)
दोहा विकास दौर विश्व व्यापार संगठन के तत्वावधान में शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी व्यापार वार्ता प्रक्रिया है। इसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक व्यापार नियमों में सुधार करना और विशेष रूप से विकासशील देशों के लिए कृषि और बाजार पहुंच जैसे क्षेत्रों में बेहतर अवसर पैदा करना है। यह दौर वार्ताओं की जटिलता और विकसित एवं विकासशील देशों के बीच हितों के टकराव के कारण लंबे समय तक चलता रहा है। यह वैश्विक व्यापार प्रणाली में समानता और न्याय लाने के प्रयासों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। यह अंतरराष्ट्रीय वाणिज्य में समावेशिता सुनिश्चित करने और विकासशील राष्ट्रों के आर्थिक हितों की रक्षा करने की दिशा में एक गंभीर प्रयास है। यह बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के भविष्य के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और निर्णायक प्रक्रिया है।

122. (B) आसियान (ASEAN)
'बैम्बू नेटवर्क' शब्द दक्षिण-पूर्वी एशिया में प्रवासी चीनी व्यवसायों के बीच मौजूद घनिष्ठ व्यापारिक और पारिवारिक संबंधों को संदर्भित करता है। इस नेटवर्क ने आसियान देशों की आर्थिक वृद्धि और क्षेत्रीय एकीकरण में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसने क्षेत्र में निवेश और व्यापार के प्रवाह को सुगम बनाकर आर्थिक सीमाओं को कम करने में मदद की है। आसियान के विकास में इन अनौपचारिक आर्थिक संबंधों का योगदान इसकी सफलता और जीवंतता का एक प्रमुख कारण माना जाता है, जो इसे और अधिक एकीकृत बनाता है। यह क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग में सांस्कृतिक और सामाजिक नेटवर्क की महत्ता को स्पष्ट रूप से उजागर करता है। यह आसियान की आर्थिक शक्ति और उसकी अद्वितीय विकास प्रक्रिया को समझने के लिए एक अनिवार्य आधार प्रदान करता है।

123. (B) स्विट्जरलैंड
स्विट्जरलैंड जी-20 का सदस्य नहीं है, क्योंकि यह समूह मुख्य रूप से दुनिया की 20 सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली अर्थव्यवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करता है। जी-20 में भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसी प्रमुख उभरती हुई शक्तियां शामिल हैं, जो वैश्विक आर्थिक एजेंडे को आकार देती हैं। स्विट्जरलैंड, हालांकि एक समृद्ध अर्थव्यवस्था है, लेकिन यह इस समूह की सदस्यता के भौगोलिक और आर्थिक मानदंडों के अंतर्गत नहीं आता है। जी-20 का फोकस व्यापक वैश्विक वित्तीय स्थिरता और अंतरराष्ट्रीय नीति समन्वय पर अधिक रहता है। यह इस मंच की विशिष्ट संरचना और उसके वैश्विक आर्थिक शासन के उद्देश्यों को स्पष्ट करता है। इसमें शामिल राष्ट्र सामूहिक रूप से वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के एक विशाल हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो इसे अत्यंत प्रभावशाली बनाता है।

124. (A) P-3, Q-4, R-1, S-2
विभिन्न क्षेत्रीय संगठनों की स्थापना अलग-अलग दशकों में हुई, जो तत्कालीन वैश्विक आवश्यकताओं को दर्शाते हैं। अमेरिकी राज्यों के संगठन की स्थापना 1948 में हुई थी। ओपेक का गठन 1960 में तेल उत्पादक देशों के हितों की रक्षा के लिए किया गया था। आसियान की स्थापना 1967 में दक्षिण-पूर्व एशिया में सहयोग बढ़ाने के लिए हुई थी। अंत में, सार्क का गठन 1985 में दक्षिण एशियाई राष्ट्रों के बीच संबंधों को सुधारने के लिए किया गया। यह कालक्रम अंतरराष्ट्रीय सहयोग के विकास और क्षेत्रीय एकीकरण के प्रयासों को स्पष्ट करता है। ये संगठन अपने-अपने क्षेत्रों में शांति, सुरक्षा और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करते हैं। यह वैश्विक कूटनीति के इतिहास में क्षेत्रीय संस्थानों के क्रमिक विकास और उनकी प्रासंगिकता को दर्शाता है।

125. (B) इसने न्यास क्षेत्रों के स्वतंत्रता की ओर संक्रमण की देखरेख के अपने शासनादेश को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया था।
न्यास परिषद की स्थापना उन क्षेत्रों के प्रशासन की देखरेख के लिए की गई थी जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्र नहीं थे। जैसे ही अंतिम न्यास क्षेत्र, पलाऊ, 1994 में स्वतंत्र हुआ, परिषद का मुख्य कार्य समाप्त हो गया। संगठन ने अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया था, इसलिए इसने अपने नियमित संचालन को निलंबित कर दिया। यह संयुक्त राष्ट्र के उन अंगों में से एक है जिसने अपने चार्टर द्वारा निर्धारित उद्देश्यों को पूर्णतः प्राप्त किया है। वर्तमान में इसकी बैठकें केवल आवश्यकतानुसार ही बुलाई जाती हैं। यह अंतरराष्ट्रीय वि-उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया में संयुक्त राष्ट्र की सफलता और उसकी ऐतिहासिक भूमिका का एक उत्कृष्ट प्रमाण है। यह संगठन के सुव्यवस्थित कार्यकरण और लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

126. (A) सहस्राब्दी विकास लक्ष्य (MDGs) और सतत विकास लक्ष्य (SDGs)।
संयुक्त राष्ट्र का वर्तमान शांति और विकास का दृष्टिकोण सतत विकास लक्ष्यों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ये लक्ष्य गरीबी मिटाने, असमानता को कम करने और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए एक वैश्विक रूपरेखा प्रदान करते हैं। संगठन का मानना है कि विकास के बिना शांति स्थाई नहीं हो सकती और शांति के बिना विकास संभव नहीं है। एसडीजी 2030 तक सभी के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने की सामूहिक प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। यह ढांचा अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए एक

Downloaded from www.pdf.tube

68. (A) निर्भरता
निर्भरता सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि विकसित और विकासशील देशों के बीच संबंध संरचनात्मक रूप से शोषणकारी हैं। इस सिद्धांत के अनुसार, 'परिधि' के देश 'केंद्र' के विकसित राष्ट्रों को कम कीमत पर कच्चा माल और सस्ता श्रम प्रदान करते हैं। बदले में, ये राष्ट्र महंगे निर्मित उत्पाद खरीदते हैं, जिससे धन का निरंतर प्रवाह विकसित देशों की ओर बना रहता है। यह प्रक्रिया विकासशील देशों को एक स्थाई आर्थिक पिछड़ेपन और विकसित राष्ट्रों पर निर्भरता की स्थिति में बनाए रखती है। यह वैश्विक पूंजीवाद के भीतर मौजूद असमानता और शोषण के चक्र को स्पष्ट रूप से उजागर करता है।

69. (B) विकास, व्यापार और सहायता।
उत्तर-दक्षिण संवाद का मुख्य केंद्र बिंदु वैश्विक आर्थिक असमानता को दूर करना है। इसमें विकासशील देशों के लिए बेहतर व्यापारिक अवसर, ऋणों की अदायगी में राहत और तकनीकी सहायता जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाती है। 'उत्तर' के विकसित देश और 'दक्षिण' के विकासशील देश इन वार्ताओं के माध्यम से एक संतुलित वैश्विक विकास मॉडल की खोज करते हैं। इस संवाद का उद्देश्य निर्धन राष्ट्रों की गरीबी कम करना और उन्हें अंतरराष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली में सक्रिय और समान भागीदार बनाना है। यह वैश्विक न्याय और सामूहिक समृद्धि की दिशा में एक महत्वपूर्ण और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।

70. (A) P-4, Q-3, R-1, S-2
ये क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय संगठन विशिष्ट ऐतिहासिक घटनाओं और उद्देश्यों से जुड़े हैं। ओपेक ने 1973 में तेल प्रतिबंध के माध्यम से अपनी वैश्विक शक्ति का परिचय दिया था। जी-20 समूह 2008 के वित्तीय संकट के बाद राष्ट्राध्यक्षों के स्तर पर अधिक प्रभावी और सक्रिय हुआ। सार्क ने दक्षिण एशिया में व्यापार बढ़ाने के लिए साफ़्टा जैसा महत्वपूर्ण समझौता किया है। आसियान की नींव 1967 की बैंकॉक घोषणा के साथ रखी गई थी। ये सभी तत्व उनके क्षेत्रीय और वैश्विक प्रभाव को परिभाषित करते हैं। ये संगठन अंतरराष्ट्रीय राजनीति और आर्थिक शासन की संरचना को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

71. (B) यूनेस्को (UNESCO)
यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, जो शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के माध्यम से वैश्विक शांति को बढ़ावा देती है। संयुक्त राष्ट्र के मुख्य अंग केवल छह हैं, जिनमें सुरक्षा परिषद, महासभा और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय शामिल हैं। विशेष एजेंसियां अपने विशिष्ट क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं, लेकिन वे आर्थिक और सामाजिक परिषद के साथ समन्वय करती हैं। यूनेस्को जैसे संगठनों का मुख्य कार्य मानवता के विकास के विशिष्ट पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना और अंतरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना है। यह वैश्विक शैक्षिक और सांस्कृतिक उत्थान के लिए एक अनिवार्य और महत्वपूर्ण वैश्विक संस्था है।

72. (B) किसी मूल प्रस्ताव को अपनाने से रोकना।
सुरक्षा परिषद के संदर्भ में वीटो शक्ति एक अत्यंत शक्तिशाली साधन है जो केवल पांच स्थाई सदस्यों के पास उपलब्ध है। यदि इनमें से कोई भी एक सदस्य किसी महत्वपूर्ण प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान करता है, तो वह प्रस्ताव पारित नहीं हो सकता। यह शक्ति किसी भी बहुमत वाले निर्णय को प्रभावी ढंग से रोकने की क्षमता प्रदान करती है। वीटो का उपयोग अक्सर स्थाई सदस्य अपने राष्ट्रीय हितों या रणनीतिक लक्ष्यों की रक्षा के लिए करते हैं। यह परिषद के भीतर शक्ति संतुलन का एक विवादास्पद हिस्सा है। यह अंतरराष्ट्रीय निर्णय लेने की प्रक्रिया में महाशक्तियों के निर्णायक प्रभाव को स्पष्ट रूप से दर्शाता है।

73. (D) 1, 2 और 3
संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों को उनकी विशिष्ट नीली टोपियों के कारण 'ब्लू हेलमेट' के नाम से जाना जाता है। ये अभियान सदैव मेजबान देश की सहमति से चलाए जाते हैं और इनका उद्देश्य शांति समझौतों को लागू करना होता है। शांति सैनिकों को बल प्रयोग की अनुमति केवल आत्मरक्षा या अपने शासनादेश की रक्षा के लिए ही दी जाती है। ये अभियान अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र के एक अनिवार्य और अत्यंत महत्वपूर्ण मानवीय उपकरण के रूप में कार्य करते हैं। यह संघर्षरत क्षेत्रों में स्थिरता बहाल करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का एक वैश्विक प्रयास है।

74. (B) चीन, जापान, दक्षिण कोरिया
"आसियान+3" एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय सहयोग ढांचा है जिसमें आसियान के दस सदस्यों के साथ तीन प्रमुख पूर्वी एशियाई अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं। चीन, जापान और दक्षिण कोरिया की भागीदारी इस मंच को आर्थिक और राजनीतिक रूप से अत्यंत प्रभावशाली बनाती है। यह ढांचा मुख्य रूप से वित्तीय स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा और व्यापारिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। इसके माध्यम से पूरा क्षेत्र वैश्विक आर्थिक चुनौतियों का सामूहिक रूप से सामना करने और आपसी विकास सुनिश्चित करने के लिए मिलकर कार्य करता है। यह एशियाई क्षेत्रीय एकीकरण और आर्थिक शक्ति को वैश्विक मंच पर सुदृढ़ करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है।

75. (A) आसियान (ASEAN)
आसियान के संचालन का एक मौलिक सिद्धांत सदस्य देशों के आंतरिक मामलों में पूर्ण अहस्तक्षेप है। यह संगठन राष्ट्रों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति अत्यधिक सम्मान प्रदर्शित करता है। इसी सिद्धांत के कारण आसियान देशों ने आपसी विवादों को दरकिनार कर आर्थिक और सामाजिक सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया है। यह दृष्टिकोण क्षेत्र में शांति बनाए रखने और सदस्य राष्ट्रों के बीच विश्वास बढ़ाने में सहायक रहा है। इसे 'आसियान शैली' के एक अनिवार्य स्तंभ के रूप में भी जाना जाता है। यह क्षेत्रीय स्थिरता और परस्पर सहयोग की एक सफल और अद्वितीय एशियाई पद्धति को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है।

NODIA

आधारित होती है। इस सिद्धांत की जड़ें मुख्य रूप से लैटिन अमेरिकी विद्वानों के अनुभवों में निहित हैं, जिन्होंने वहां की आर्थिक चुनौतियों का विश्लेषण किया था। यह वैश्विक पूंजीवाद के प्रति एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण रखता है और इसे असमानता का मुख्य कारण मानता है। यह सिद्धांत मानता है कि जब तक अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संरचनाओं में बदलाव नहीं होगा, तब तक परिधि के देशों का विकास संभव नहीं है। यह वैश्विक अर्थव्यवस्था में मौजूद संरचनात्मक बाधाओं और विकासशील राष्ट्रों के स्थाई पिछड़ेपन के कारणों को गहराई से उजागर करता है। यह अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंधों में न्याय और समानता की आवश्यकता पर बल देने वाला एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली सैद्धांतिक ढांचा प्रस्तुत करता है।

134. (B) गैर-भेदभाव का सिद्धांत (MFN और राष्ट्रीय व्यवहार)।
विश्व व्यापार संगठन की व्यापार प्रणाली गैर-भेदभाव के दो स्तंभों पर टिकी हुई है: सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र और राष्ट्रीय व्यवहार। एमएफएन सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि एक सदस्य द्वारा किसी दूसरे को दी गई व्यापारिक छूट सभी सदस्यों को प्राप्त हो। राष्ट्रीय व्यवहार का अर्थ है कि आयातित वस्तुओं के साथ बाजार में प्रवेश के बाद घरेलू वस्तुओं जैसा ही व्यवहार किया जाए। ये नियम अंतरराष्ट्रीय व्यापार में पारदर्शिता, पूर्वानुमान और निष्पक्षता को बढ़ावा देते हैं, जिससे वैश्विक वाणिज्य के सुचारू संचालन में सहायता मिलती है। यह बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली में विश्वास बनाए रखने और छोटे राष्ट्रों को शक्तिशाली व्यापारिक साझेदारों के भेदभावपूर्ण व्यवहार से बचाने के लिए अनिवार्य है। यह वैश्विक बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा और समान अवसरों को सुनिश्चित करने का एक प्रभावी कानूनी तंत्र प्रदान करता है।

135. (A) विकासशील देशों के बीच सामूहिक आत्मनिर्भरता।
दक्षिण-दक्षिण सहयोग विकासशील राष्ट्रों के बीच एकजुटता और आपसी सहायता का एक सशक्त माध्यम है। यह इस विचार पर आधारित है कि ये देश एक-दूसरे के अनुभवों, संसाधनों और तकनीकी ज्ञान को साझा करके अपनी सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ा सकते हैं। यह सहयोग उत्तरी देशों पर उनकी ऐतिहासिक निर्भरता को कम करने में सहायक होता है। इसके माध्यम से विकासशील राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपनी साझा चिंताओं को अधिक प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। यह वैश्विक दक्षिण के सशक्तिकरण की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यह राष्ट्रों के बीच समानता और परस्पर सम्मान के सिद्धांतों पर आधारित है, जो वैश्विक विकास के लिए एक नई और न्यायपूर्ण दिशा प्रदान करता है। यह विकासशील राष्ट्रों की सामूहिक शक्ति और उनकी स्वायत्तता को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुदृढ़ करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है।

136. (A) 4, 2, 1, 3
अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों की स्थापना का कालक्रम वैश्विक सहयोग के क्रमिक विकास को दर्शाता है। सबसे पहले 1960 में ओपेक का गठन तेल उत्पादक देशों के हितों के लिए हुआ था। इसके बाद 1967 में आसियान की स्थापना दक्षिण-पूर्व एशिया में क्षेत्रीय स्थिरता के लिए की गई। सार्क का गठन 1985 में दक्षिण एशियाई देशों के बीच संबंधों को सुधारने के लिए हुआ। अंत में, 1999 में स्थापित जी-20 को 2008 में राष्ट्राध्यक्षों के स्तर के शिखर सम्मेलन के रूप में उन्नत किया गया था। यह विकास क्रम अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में सहयोग के बदलते स्वरूप और वैश्विक आर्थिक एवं सुरक्षा चुनौतियों के समाधान हेतु नए मंचों के निर्माण को स्पष्ट रूप से उजागर करता है। यह क्षेत्रीय एकीकरण और वैश्विक नीतिगत समन्वय की दिशा में राष्ट्रों के बढ़ते प्रयासों का एक व्यवस्थित और तार्किक ऐतिहासिक प्रमाण है।

137. (C) यह निर्णयों को लागू करने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी संस्थानों पर निर्भर करता है।
'आसियान शैली' की मुख्य विशेषता इसकी अनौपचारिकता और कानूनी रूप से बाध्यकारी बाध्यताओं का अभाव है। यह पद्धति सदस्य देशों के बीच आम सहमति और निरंतर परामर्श के माध्यम से निर्णय लेने पर बल देती है। इसमें कठोर कानूनी ढांचे के स्थान पर आपसी विश्वास और लचीलेपन को प्राथमिकता दी जाती है। यह दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि कोई भी निर्णय किसी सदस्य राष्ट्र की संप्रभुता को चुनौती न दे। अतः, आसियान की सफलता का आधार इसकी संस्थागत मजबूती नहीं, बल्कि इसकी अनूठी कूटनीतिक प्रक्रिया है। यह क्षेत्रीय स्थिरता और परस्पर सहयोग की एक सफल और अद्वितीय एशियाई पद्धति को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। यह विविधतापूर्ण राजनीतिक प्रणालियों के बावजूद राष्ट्रों को एक साथ लाने और उनमें सहयोग की भावना विकसित करने में अत्यंत सहायक सिद्ध हुई है।

138. (A) वाशिंगटन, डी.सी., यूएसए
अमेरिकी राज्यों के संगठन का मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन, डी.सी. में स्थित है। यह स्थान संगठन के प्रशासनिक कार्यों और सदस्य देशों के बीच कूटनीतिक वार्ताओं का मुख्य केंद्र है। मुख्यालय का यहाँ स्थित होना अंतरराष्ट्रीय संबंधों में अमेरिका की महत्वपूर्ण भूमिका को भी दर्शाता है। यह सचिवालय संगठन के विभिन्न सम्मेलनों, मानवाधिकार आयोगों और विकासात्मक परियोजनाओं के समन्वय के लिए उत्तरदायी है। यह क्षेत्रीय सहयोग और पश्चिमी गोलार्ध की एकजुटता को मजबूत करने के प्रयासों का केंद्र बिंदु है। यह संगठन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और उसके कार्यक्षेत्र की व्यापकता को प्रतिबिंबित करता है। यह पश्चिमी गोलार्ध के राष्ट्रों के बीच कूटनीतिक संवाद और आपसी सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए एक महत्वपूर्ण और स्थाई संस्थागत आधार प्रदान करता है।

139. (C) A सही है लेकिन R गलत है।
जी-20 में वास्तव में यूरोपीय संघ एक सदस्य के रूप में शामिल है, जो इस समूह की वैश्विक आर्थिक पहुंच को बढ़ाता है। हालांकि, यह कहना गलत है कि जी-20 का ध्यान केवल राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों पर है। इसके विपरीत, जी-20 की स्थापना और इसका मुख्य कार्य अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग, वित्तीय स्थिरता और व्यापारिक नीतियों का समन्वय करना है। यद्यपि समय-समय पर अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होती है, लेकिन आर्थिक और वित्तीय मामले ही इसके एजेंडे का मूल

Click Here to Buy book on Amazon

बनाए रखने के लिए एक स्थाई वित्तीय आधार प्रदान करता है। यह वैश्विक सहयोग में आर्थिक शक्ति और सुरक्षा उत्तरदायित्वों के बीच के तार्किक समन्वय को स्पष्ट करता है। यह प्रणाली शांति अभियानों के प्रभावी क्रियान्वयन और उनकी वित्तीय स्थिरता को सुदृढ़ करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है।

188. (C) शक्ति के कई केंद्रों वाली दुनिया, जो किसी एक राष्ट्र के प्रभुत्व को रोकती है।
बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था का अर्थ है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में शक्ति केवल एक या दो महाशक्तियों के पास न होकर कई देशों या समूहों के पास विभाजित होनी चाहिए। भारत का मानना है कि ऐसी व्यवस्था अधिक लोकतांत्रिक और न्यायसंगत होती है, क्योंकि यह किसी एक राष्ट्र की मनमानी को रोकती है। इसमें संवाद और आपसी सहमति को अधिक महत्व मिलता है, जो वैश्विक स्थिरता के लिए आवश्यक है। भारत स्वयं को इस बहुध्रुवीय व्यवस्था के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में देखता है, जो शांति और न्याय को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। यह दृष्टिकोण अंतरराष्ट्रीय संबंधों में समानता और समावेशिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक प्रभावी रणनीतिक ढांचा प्रदान करता है। बहुध्रुवीयता वैश्विक चुनौतियों का सामूहिक समाधान खोजने और राष्ट्रों के बीच शक्ति के संतुलित वितरण को सुदृढ़ करने के लिए अनिवार्य है। यह भारत की स्वतंत्र और जिम्मेदार वैश्विक भूमिका का आधार है।

189. (B) गुटनिरपेक्षता (Non-Alignment)।
शीत युद्ध के दौरान भारत की मध्यस्थ भूमिका उसकी गुटनिरपेक्ष नीति का एक स्वाभाविक विस्तार थी। भारत ने किसी भी सैन्य गुट में शामिल न होकर अपनी निष्पक्षता बनाए रखी, जिससे उसे अमेरिका और सोवियत संघ दोनों के साथ संवाद करने की सुविधा मिली। इस नीति ने भारत को कोरियाई युद्ध जैसे संकटों में एक शांतिदूत के रूप में कार्य करने का अवसर प्रदान किया। यह दर्शाता है कि गुटनिरपेक्षता केवल निष्क्रियता नहीं थी, बल्कि यह अंतरराष्ट्रीय शांति के लिए एक सक्रिय और सकारात्मक राजनयिक दृष्टिकोण था जिसने भारत की प्रतिष्ठा को वैश्विक स्तर पर बढ़ाया। यह भारत की रणनीतिक स्वायत्तता और वैश्विक संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के प्रति उसकी अडिग प्रतिबद्धता का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसने भारत को अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक संतुलनकारी शक्ति के रूप में स्थापित किया, जो आज भी भारतीय विदेश नीति के नैतिक और व्यावहारिक आधार के रूप में अत्यंत प्रासंगिक और प्रभावशाली बना हुआ है।

190. (A) हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री डकैती।
भारत की समुद्री सुरक्षा के लिए हिंद महासागर में समुद्री डकैती और व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा एक प्रमुख चुनौती है। भारत का अधिकांश अंतरराष्ट्रीय व्यापार समुद्री मार्गों से होता है, इसलिए इन मार्गों का सुरक्षित रहना देश की आर्थिक स्थिरता के लिए अत्यंत अनिवार्य है। भारतीय नौसेना इन क्षेत्रों में निरंतर गश्त करती है ताकि समुद्री लुटेरों के खतरों को रोका जा सके। यह सुरक्षा चिंता क्षेत्रीय स्थिरता और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के महत्व को भी रेखांकित करती है। भारत इस क्षेत्र में एक सुरक्षा प्रदाता के रूप में अपनी भूमिका को निरंतर मजबूत कर रहा है। यह समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने और वैश्विक वाणिज्य के सुचारु प्रवाह को सुदृढ़ करने की दिशा में भारत की रणनीतिक सक्रियता को दर्शाता है। हिंद महासागर क्षेत्र की सुरक्षा भारत के राष्ट्रीय हितों और क्षेत्रीय शांति के लिए सर्वोपरि है, जो कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर निरंतर ध्यान केंद्रित करने की मांग करती है।

191. (A) किसी राज्य की विदेश नीति को लागू करना।
कूटनीति वह अनिवार्य माध्यम है जिसके द्वारा कोई राष्ट्र अपने विदेश नीति के लक्ष्यों और सिद्धांतों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्रियान्वित करता है। यह बातचीत, समझौतों, और प्रतिनिधित्व का एक सूक्ष्म अभ्यास है जो बिना युद्ध के राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने का प्रयास करता है। एक कुशल कूटनीति के जरिए राष्ट्र गठबंधन बनाते हैं और वैश्विक समस्याओं के समाधान खोजते हैं। यह अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में शांति और सहयोग बनाए रखने का प्राथमिक साधन है। बिना कूटनीति के, राष्ट्रों के बीच के संबंध केवल शक्ति और संघर्ष पर आधारित रह जाएंगे। यह अंतरराष्ट्रीय राजनीति के जटिल अंतर्संबंधों को प्रबंधित करने और राष्ट्रहितों के साथ वैश्विक लक्ष्यों के बीच तालमेल बनाने का एक अनिवार्य और प्रभावी माध्यम है। कूटनीति की सफलता राष्ट्र की प्रतिष्ठा और उसके वैश्विक प्रभाव को सुदृढ़ करती है, जिससे शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व और न्यायसंगत अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का निर्माण संभव होता है।

192. (A) केवल 1 और 2
भारतीय विदेश नीति के आधारभूत सिद्धांतों में पंचशील और गुटनिरपेक्षता शामिल हैं, जो शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व और रणनीतिक स्वायत्तता पर बल देते हैं। भारत ने सदैव अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए सैन्य गठबंधनों से दूरी बनाए रखी है, इसलिए यह कहना गलत है कि भारत ने कभी भी सुरक्षा के लिए सैन्य गुटों में शामिल होने की नीति अपनाई थी। इसके विपरीत, भारत ने उपनिवेशवाद और रंगभेद जैसी अमानवीय व्यवस्थाओं का अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कड़ा विरोध किया है। ये विशेषताएं भारत को एक न्यायप्रिय और शांतिप्रिय राष्ट्र के रूप में परिभाषित करती हैं। यह अंतरराष्ट्रीय संबंधों में भारत के नैतिक नेतृत्व और उसकी स्वतंत्र वैश्विक भूमिका को स्पष्ट रूप से उजागर करता है। रणनीतिक स्वायत्तता और शांतिपूर्ण संवाद के प्रति भारत की यह दीर्घकालिक प्रतिबद्धता आज भी उसकी कूटनीतिक प्राथमिकताओं का मूल आधार बनी हुई है, जो वैश्विक स्थिरता और न्यायसंगत विश्व व्यवस्था को सुदृढ़ करने के प्रयासों को नई दिशा प्रदान करती है।

193. (B) P-3, Q-1, R-4, S-2
ये अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय अवधारणाएं विभिन्न समूहों और ऐतिहासिक संदर्भों से जुड़ी हुई हैं। नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की मांग मुख्य रूप से जी-77 देशों द्वारा उठाई गई थी। आसियान क्षेत्रीय मंच एशिया-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा संवाद के लिए आसियान की एक महत्वपूर्ण पहल है। ओपेक का नाम 1970 के दशक के तेल की कीमतों के झटकों और ऊर्जा राजनीति से गहराई से जुड़ा हुआ है। अमेरिकी राज्यों का संगठन

NODIA

अभियानों के लिए एक नया और प्रभावी रणनीतिक ढांचा तैयार किया जो आज भी अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अत्यंत प्रासंगिक है।

146. (A) उन्हें पर्याप्त रूप से वित्तपोषित करने के लिए सदस्य देशों की इच्छा।
संयुक्त राष्ट्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि शांति स्थापना अभियानों की मांग तो बढ़ रही है, लेकिन सदस्य राष्ट्रों की इन्हें पर्याप्त धन देने की इच्छा और क्षमता सीमित होती जा रही है। वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण कई महत्वपूर्ण अभियानों को प्रभावी ढंग से संचालित करना कठिन हो जाता है। कुछ बड़े योगदानकर्ता देश अक्सर राजनीतिक कारणों से अपने अंशदान में कटौती करते हैं। यह स्थिति संगठन की कार्यक्षमता को प्रभावित करती है और इसे अपनी शांति बनाए रखने की जिम्मेदारियों को पूरा करने में कमजोर बनाती है। यह अंतरराष्ट्रीय समुदाय के भीतर सामूहिक वित्तीय जिम्मेदारी और राजनीतिक प्रतिबद्धता की कमी को उजागर करता है। वैश्विक शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र को एक स्थाई और पर्याप्त वित्तीय आधार प्रदान करना अनिवार्य है, जो सदस्य राष्ट्रों के आपसी सहयोग और विश्वास पर निर्भर करता है।

147. (B) पारस्परिक अहस्तक्षेप।
पंचशील का एक मूल सिद्धांत यह है कि कोई भी देश दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। यह सिद्धांत राष्ट्रों की संप्रभुता और उनकी राजनीतिक व्यवस्था को चुनने के अधिकार का सम्मान करने पर बल देता है। भारतीय विदेश नीति में इसे एक अनिवार्य स्तंभ माना गया है ताकि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में विश्वास और शांति बनी रहे। अहस्तक्षेप की यह नीति विवादों को रोकने और राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक आवश्यक आधार प्रदान करने का कार्य करती है। यह अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति भारत की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता और उसके नैतिक आदर्शों को प्रतिबिंबित करता है। यह सिद्धांत राष्ट्रों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों और संप्रभु समानता सुनिश्चित करने के लिए एक अनिवार्य शर्त है। यह भारत की रणनीतिक स्वायत्तता और पड़ोसी राष्ट्रों के प्रति उसके सम्मानजनक दृष्टिकोण का प्रमाण है।

148. (D) भेदभावपूर्ण है, जो परमाणु "संपन्न" और "विहीन" वर्ग बनाती है।
भारत ने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने से इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि वह इसे एक भेदभावपूर्ण दस्तावेज मानता है। भारत का तर्क है कि यह संधि उन देशों को अपने परमाणु हथियार रखने की अनुमति देती है जिन्होंने 1967 से पहले परीक्षण किए थे, जबकि अन्य देशों पर प्रतिबंध लगाती है। यह व्यवस्था दुनिया को दो वर्गों में विभाजित करती है और वैश्विक निशस्त्रीकरण की दिशा में कोई ठोस समय सीमा प्रदान नहीं करती। भारत का रुख सदैव सार्वभौमिक और समान निशस्त्रीकरण के पक्ष में रहा है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा और वैश्विक न्याय के सिद्धांतों के प्रति भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह अंतरराष्ट्रीय संबंधों में समानता और निष्पक्षता की मांग करने वाला एक साहसिक और रणनीतिक निर्णय था। भारत का मानना है कि परमाणु मुक्त विश्व के लिए सभी राष्ट्रों को समान रूप से उत्तरदायी होना चाहिए।

149. (D) दक्षिण-पूर्व और पूर्व एशियाई देशों के साथ आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को सुदृढ़ करना।
'लुक ईस्ट' नीति की शुरुआत 1990 के दशक में भारत की अर्थव्यवस्था को दक्षिण-पूर्व और पूर्व एशिया के तेजी से बढ़ते बाजारों के साथ जोड़ने के उद्देश्य से की गई थी। इसका लक्ष्य व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देना, निवेश आकर्षित करना और क्षेत्र के साथ सांस्कृतिक एवं रणनीतिक जुड़ाव को गहरा करना था। शीत युद्ध के बाद के बदलते वैश्विक परिदृश्य में यह नीति भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। इसने आसियान देशों के साथ भारत की साझेदारी को एक नई ऊंचाई दी और क्षेत्रीय एकीकरण को मजबूत किया। यह नीति की गतिशीलता और बदलती वैश्विक परिस्थितियों के अनुरूप भारत की कूटनीतिक और आर्थिक दिशा को नया विस्तार प्रदान करने का एक सफल प्रयास था। इसने भारत को एशिया-प्रशांत क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण आर्थिक और रणनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित करने में मदद की।

150. (A) P-3, Q-2, R-1, S-4
भारतीय विदेश नीति की प्रमुख पहलों का संबंध विभिन्न प्रधानमंत्रियों और उनके कार्यकाल से है। पंचशील समझौता जवाहरलाल नेहरू के समय में शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के आधार के रूप में उभरा। गुजराल सिद्धांत आई.के. गुजराल द्वारा पड़ोसियों के प्रति उदारता की नीति के रूप में लाया गया। 'लुक ईस्ट' नीति पी.वी. नरसिम्हा राव के कार्यकाल में आर्थिक सुधारों के साथ शुरू हुई। शिमला समझौता इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के बीच युद्ध के बाद शांति स्थापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक ऐतिहासिक मील का पत्थर था। ये सभी पहल भारत की विदेश नीति के विकासवादी और अनुकूलन योग्य चरित्र को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करती हैं। प्रत्येक प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल में वैश्विक परिस्थितियों के अनुरूप भारत की कूटनीतिक दिशा को सफलतापूर्वक नई गति और विस्तार प्रदान किया, जिससे राष्ट्रहितों की प्रभावी रूप से रक्षा की जा सके।

151. (B) यह बातचीत, प्रतिनिधित्व और संचार के माध्यम से विदेश नीति का कार्यान्वयन है।
कूटनीति किसी राष्ट्र की विदेश नीति के लक्ष्यों को धरातल पर उतारने की कला और प्रक्रिया है। इसके माध्यम से एक देश अन्य राष्ट्रों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ निरंतर संवाद और बातचीत करके अपने हितों की रक्षा करता है। कूटनीति का मुख्य कार्य विवादों को सुलझाना, गठबंधन बनाना और आपसी सहयोग के नए अवसर खोजना है। यह एक शांतिपूर्ण उपकरण है जो अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में स्थिरता और समझ विकसित करने में सहायक होता है। एक सफल कूटनीति राष्ट्र की प्रतिष्ठा और उसके वैश्विक प्रभाव को सुदृढ़ करती है। यह अंतरराष्ट्रीय राजनीति के जटिल अंतर्संबंधों को प्रबंधित करने और राष्ट्रों के बीच टकराव को कम करने का एक अनिवार्य माध्यम है। यह

NODIA

164. (C) सुरक्षा परिषद की स्थाई सदस्यता और वीटो शक्ति वर्तमान वैश्विक वास्तविकताओं को नहीं दर्शाती है।
संयुक्त राष्ट्र की सबसे बड़ी आलोचना इसकी सुरक्षा परिषद की संरचना को लेकर है, जो आज भी 1945 के शक्ति संतुलन पर आधारित है। पांच देशों के पास वीटो शक्ति होना और उभरती हुई शक्तियों को स्थाई सदस्यता न मिलना अलोकतांत्रिक माना जाता है। यह ढांचा अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया के बड़े हिस्से का उचित प्रतिनिधित्व नहीं करता है। इसके कारण परिषद की निर्णय लेने की प्रक्रिया अक्सर पक्षपाती और अप्रभावी हो जाती है। सुधार के बिना, संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक वैधता और प्रतिनिधित्व पर निरंतर सवाल उठते रहते हैं। यह अंतरराष्ट्रीय शासन प्रणाली में समानता और समावेशिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ी बाधा है। सुरक्षा परिषद को अधिक प्रतिनिधि और प्रभावी बनाने के लिए इसमें लोकतांत्रिक सुधारों का होना अनिवार्य है ताकि यह वर्तमान बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था और उसकी चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना कर सके।

165. (A) गठबंधन बनाना, प्रस्तावों पर बातचीत करना और राष्ट्रीय एवं समूह हितों के लिए संयुक्त राष्ट्र मंच का लाभ उठाना।
संयुक्त राष्ट्र के भीतर कूटनीति एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ राष्ट्र अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए बहुपक्षीय संवाद का उपयोग करते हैं। इसमें विभिन्न देश समान हितों वाले समूहों के साथ मिलकर काम करते हैं ताकि वे मतदान के परिणामों को प्रभावित कर सकें। यह कूटनीति केवल शांति बनाए रखने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक सहायता और मानवाधिकारों जैसे मुद्दों पर वैश्विक राय बनाने का भी एक साधन है। यह दर्शाता है कि अंतरराष्ट्रीय संस्थान कैसे राष्ट्रों के बीच प्रतिस्पर्धा और सहयोग का एक मंच बनते हैं। यह बहुपक्षीय कूटनीति का एक अनिवार्य हिस्सा है जहाँ राष्ट्रहित और वैश्विक लक्ष्यों के बीच संतुलन बनाने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। यह वैश्विक शासन के मानदंडों को आकार देने और सामूहिक चुनौतियों का सामना करने के लिए राष्ट्रों के बीच कूटनीतिक कौशल और रणनीतिक समन्वय की महत्ता को रेखांकित करता है।

166. (B) स्थाई और अस्थाई दोनों श्रेणियों में सुरक्षा परिषद का विस्तार।
विकासशील देशों की संयुक्त राष्ट्र सुधारों में एक प्रमुख मांग सुरक्षा परिषद को अधिक प्रतिनिधि बनाने की रही है। वे चाहते हैं कि स्थाई और अस्थाई दोनों श्रेणियों में सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए ताकि वैश्विक दक्षिण के देशों को उचित स्थान मिल सके। उनका मानना है कि वर्तमान परिषद में केवल कुछ विकसित राष्ट्रों का प्रभुत्व है, जो पूरी दुनिया के हितों का प्रतिनिधित्व नहीं करता। यह विस्तार परिषद की निर्णय लेने की प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता और लोकतांत्रिक वैधता लाएगा, जो आज की बहुध्रुवीय दुनिया के लिए अनिवार्य है। यह अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रबंधन में विकासशील राष्ट्रों की न्यायसंगत भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में एक गंभीर प्रयास है। सुरक्षा परिषद में सुधार के बिना संयुक्त राष्ट्र की प्रभावशीलता और उसकी वैश्विक स्वीकार्यता को सुदृढ़ करना संभव नहीं है, जो वैश्विक न्याय की दिशा में एक आवश्यक कदम है।

167. (D) कथन I गलत है, लेकिन कथन II गलत है।
संयुक्त राष्ट्र के शांति स्थापना अभियानों का अपना एक अलग और विशेष बजट होता है, जो संगठन के नियमित प्रशासनिक बजट से पूर्णतः भिन्न है। सदस्य राष्ट्रों को इन अभियानों के लिए अंशदान का एक अलग पैमाना अपनाना पड़ता है, जिसमें सुरक्षा परिषद के स्थाई सदस्यों पर अधिक वित्तीय जिम्मेदारी डाली जाती है। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि शांति अभियानों के लिए आवश्यक संसाधन नियमित बजट की सीमाओं से प्रभावित न हों। अतः, वित्तपोषण की ये दोनों प्रणालियां अपनी संरचना और उद्देश्यों में एक-दूसरे से काफी अलग हैं। यह संगठन की उन वित्तीय नीतियों का हिस्सा है जो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए सामूहिक वित्तीय प्रतिबद्धता और जिम्मेदारी को स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं। यह शांति अभियानों के प्रभावी क्रियान्वयन और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए एक अनिवार्य और महत्वपूर्ण संस्थागत ढांचा प्रदान करता है।

168. (B) विवादों के शांतिपूर्ण समाधान में विश्वास।
भारत की मध्यस्थ भूमिका उसके प्राचीन और आधुनिक मूल्यों का संगम है, जो संघर्ष के स्थान पर संवाद को प्राथमिकता देती है। भारत का यह मानना है कि अंतरराष्ट्रीय विवादों को बिना बल प्रयोग के बातचीत के माध्यम से सुलझाया जाना चाहिए। यह दृष्टिकोण भारत को विभिन्न संघर्षों में एक निष्पक्ष और विश्वसनीय मध्यस्थ के रूप में उभरने में सहायता प्रदान करता है। शांतिपूर्ण समाधान की यह प्रतिबद्धता भारतीय विदेश नीति के उस नैतिक चरित्र को दर्शाती है जो वैश्विक स्थिरता और न्यायसंगत व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। यह अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति भारत की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता और उसके कूटनीतिक कौशल का प्रमाण है। भारत की यह भूमिका क्षेत्रीय और वैश्विक तनावों को कम करने और मानवीय संकटों को सुलझाने में महत्वपूर्ण सिद्ध हुई है। यह अंतरराष्ट्रीय संबंधों में शांतिपूर्ण संवाद और सहयोग की महत्ता को रेखांकित करता है।

169. (C) पूर्व-खाली हमलों का अधिकार।
पंचशील के पांच सिद्धांतों में संप्रभुता का सम्मान, अनाक्रमण, अहस्तक्षेप, समानता और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व शामिल हैं। "पूर्व-खाली हमलों का अधिकार" इन सिद्धांतों के पूर्णतः विरुद्ध है, क्योंकि यह आक्रामकता और बल प्रयोग को बढ़ावा देता है। पंचशील का मूल उद्देश्य राष्ट्रों के बीच विश्वास का वातावरण बनाना और युद्ध की संभावनाओं को कम करना था। ये सिद्धांत किसी भी देश को दूसरे पर बिना उकसावे के हमला करने की अनुमति नहीं देते। अतः, यह विचार पंचशील के शांतिपूर्ण और सहयोगात्मक आदर्शों के विपरीत एक सैन्यवादी दृष्टिकोण है। यह अंतरराष्ट्रीय संबंधों में शांतिपूर्ण संवाद और परस्पर सम्मान की नींव रखने वाले आधारभूत सिद्धांतों को चुनौती देता है। पंचशील के सिद्धांत आज भी भारत की विदेश नीति के नैतिक

Downloaded from www.pdf.tube

ढांचा प्रदान करता है। यह वैश्विक बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा और समानता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण संस्थागत सुधार सिद्ध हुआ है।

158. (B) नव-उपनिवेशवाद
नव-उपनिवेशवाद उस स्थिति को दर्शाता है जहाँ पूर्व औपनिवेशिक शक्तियां स्वतंत्र राष्ट्रों पर अप्रत्यक्ष आर्थिक और सांस्कृतिक नियंत्रण बनाए रखती हैं। यद्यपि ये राष्ट्र अब कानूनी रूप से स्वतंत्र हैं, परंतु उनकी अर्थव्यवस्थाएं और नीतियां अभी भी विकसित देशों के हितों द्वारा संचालित होती हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों और अंतरराष्ट्रीय ऋणों के माध्यम से यह नियंत्रण स्थापित किया जाता है। इसके अतिरिक्त, सांस्कृतिक प्रभाव के जरिए इन देशों की बौद्धिक स्वायत्तता को भी प्रभावित किया जाता है। यह आधुनिक समय में शोषण का एक नया और सूक्ष्म स्वरूप माना जाता है। यह स्वतंत्र राष्ट्रों की आर्थिक संप्रभुता और उनके स्वावलंबन के संघर्ष को प्रतिबिंबित करता है। यह अवधारणा अंतरराष्ट्रीय संबंधों में आर्थिक और सांस्कृतिक शक्ति के अप्रत्यक्ष रूपों को समझने के लिए अनिवार्य है। यह वैश्विक स्तर पर संप्रभुता की वास्तविक सीमाओं को गहराई से उजागर करती है।

159. (C) 75%
जी-20 समूह की महत्ता का एक प्रमुख कारण वैश्विक व्यापार में इसकी विशाल हिस्सेदारी है, जो लगभग 75 प्रतिशत तक पहुँचती है। इस समूह में दुनिया की सभी प्रमुख व्यापारिक शक्तियां शामिल हैं, जो वैश्विक वाणिज्य की दिशा और नियमों को प्रभावित करती हैं। उनकी सामूहिक आर्थिक शक्ति उन्हें अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणालियों में सुधार करने और व्यापारिक बाधाओं को कम करने के लिए एक निर्णायक मंच प्रदान करती है। यह उच्च प्रतिशत वैश्विक अर्थव्यवस्था के सुचारु संचालन में जी-20 की अनिवार्य और अत्यंत प्रभावशाली भूमिका को स्पष्ट रूप से उजागर करता है। यह इस मंच की वैश्विक स्वीकार्यता और इसके निर्णयों की आर्थिक व्यापकता को भी प्रतिबिंबित करता है। जी-20 की नीतियों और इसके नीतिगत समन्वय का वैश्विक बाजारों और आर्थिक स्थिरता पर सीधा और गहरा प्रभाव पड़ता है, जो इसे अंतरराष्ट्रीय आर्थिक शासन का एक अपरिहार्य स्तंभ बनाता है।

160. (B) 'A' और 'R' दोनों सही हैं और 'R', 'A' की सही व्याख्या है।
आसियान क्षेत्रीय मंच एशिया में सुरक्षा संवाद का एक प्रमुख संस्थान है जहाँ सदस्य देश महत्वपूर्ण क्षेत्रीय चिंताओं पर चर्चा करते हैं। यह मंच वास्तव में आम सहमति और अहस्तक्षेप के सिद्धांतों पर आधारित है, जिससे सभी प्रतिभागियों को सहजता का अनुभव होता है। हालांकि, ये सिद्धांत मंच की कार्यप्रणाली की विशेषताएं तो हैं, लेकिन वे अकेले यह नहीं समझाते कि यह एकमात्र या सबसे प्रमुख मंच क्यों है। इसका महत्व इसमें भाग लेने वाली प्रमुख वैश्विक शक्तियों और इसकी समावेशी प्रकृति के कारण भी अत्यंत व्यापक है। यह मंच निवारक कूटनीति के माध्यम से संघर्षों को टालने और क्षेत्रीय शांति बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए बहुपक्षीय संवाद की महत्ता को रेखांकित करता है। यह एशिया-प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था का एक अनिवार्य और प्रभावी स्तंभ सिद्ध हुआ है।

161. (C) प्रमुख समझौतों पर घोषणात्मक चरण से कार्यान्वयन चरण तक प्रभावी ढंग से आगे बढ़ना।
सार्क की एक बड़ी असफलता यह रही है कि यह शिखर सम्मेलनों में किए गए वादों और हस्ताक्षरित समझौतों को धरातल पर उतारने में असमर्थ रहा है। संगठन के भीतर निर्णयों के कार्यान्वयन की प्रक्रिया अत्यंत धीमी और नौकरशाही की बाधाओं से घिरी हुई है। कई महत्वपूर्ण पहल, जैसे साफ़्टा, राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी के कारण अपने पूर्ण लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकीं। घोषणाओं और वास्तविक कार्रवाई के बीच की यह गहरी खाई सार्क की प्रभावशीलता और क्षेत्रीय विकास की उसकी क्षमता पर प्रश्नचिह्न लगाती है। यह क्षेत्रीय सहयोग की राह में एक महत्वपूर्ण चुनौती और संरचनात्मक दुर्बलता है। दक्षिण एशियाई क्षेत्र के समग्र विकास और एकीकरण के लिए इन घोषणाओं का समयबद्ध और प्रभावी कार्यान्वयन अनिवार्य है। यह संगठन की भविष्य की प्रासंगिकता और विश्वसनीयता के लिए एक निर्णायक कारक बना हुआ है।

162. (C) नाइजीरिया
ओपेक की स्थापना 1960 में बगदाद सम्मेलन के दौरान हुई थी, जहाँ ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला इसके पांच संस्थापक सदस्य थे। नाइजीरिया इस संगठन में काफी समय बाद, वर्ष 1971 में शामिल हुआ था। संस्थापक राष्ट्रों ने अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार में अपनी संप्रभुता को पुनः स्थापित करने और विदेशी कंपनियों के प्रभुत्व को कम करने के लिए यह पहल की थी। यद्यपि नाइजीरिया आज ओपेक का एक अत्यंत प्रभावशाली सदस्य है, परंतु यह उन मूल राष्ट्रों में शामिल नहीं था जिन्होंने इसे आरम्भ किया था। यह संगठन के विस्तार और तेल उत्पादक देशों के बीच बढ़ती एकजुटता को दर्शाता है। ओपेक की स्थापना वैश्विक ऊर्जा राजनीति में विकासशील देशों की शक्ति को सुदृढ़ करने की दिशा में एक ऐतिहासिक मोड़ था। यह प्राकृतिक संसाधनों पर संप्रभु नियंत्रण और अंतरराष्ट्रीय बाजार में उत्पादकों के सामूहिक हितों की रक्षा का प्रतीक है।

163. (C) ओएएस (OAS)
इंटर-अमेरिकन डेमोक्रेटिक चार्टर अमेरिकी राज्यों के संगठन का एक अत्यंत शक्तिशाली और महत्वपूर्ण उपकरण है। यह चार्टर सदस्य देशों को लोकतंत्र के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए जवाबदेह बनाता है। यदि किसी देश में संवैधानिक व्यवस्था को अवैध रूप से बाधित किया जाता है, तो ओएएस उसे निलंबित करने का ऐतिहासिक निर्णय ले सकता है। यह प्रावधान संगठन की इस मान्यता को दर्शाता है कि क्षेत्रीय शांति और विकास के लिए लोकतंत्र अनिवार्य है। यह पश्चिमी गोलार्ध में लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने के लिए एक अद्वितीय कानूनी ढांचा प्रदान करता है। यह क्षेत्रीय स्थिरता और संप्रभुता के सम्मान के साथ-साथ लोकतांत्रिक शासन प्रणालियों की मजबूती और उनके संरक्षण को सर्वोपरि मानता है। यह पश्चिमी गोलार्ध के राष्ट्रों के बीच लोकतांत्रिक एकजुटता और सामूहिक सुरक्षा के प्रति उनकी साझा प्रतिबद्धता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।

NODIA

वैश्विक मंच पर देश के दृष्टिकोण को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने और सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संवाद का वातावरण तैयार करने में निर्णायक भूमिका निभाती है।

152. (B) भारत और उसके छोटे पड़ोसियों के बीच आकार, अर्थव्यवस्था और सैन्य शक्ति में महत्वपूर्ण अंतर।
दक्षिण एशिया में भारत की विशाल भौगोलिक स्थिति, विशाल जनसंख्या और मजबूत अर्थव्यवस्था इसे अन्य पड़ोसियों की तुलना में बहुत बड़ा बनाती है। इस "असममिति" के कारण अक्सर पड़ोसी देशों में असुरक्षा या प्रभुत्व का डर पैदा हो जाता है। छोटे राष्ट्र अपनी संप्रभुता को लेकर चिंतित रहते हैं, जिससे आपसी संबंधों में जटिलताएं आती हैं। भारत को अपने संबंधों को संतुलित करने के लिए इस विसंगति को समझना और विश्वास निर्माण के माध्यम से इसे दूर करना आवश्यक होता है। यह दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय राजनीति का एक अनिवार्य और संवेदनशील पहलू है। क्षेत्रीय स्थिरता और सहयोग सुनिश्चित करने के लिए भारत की ओर से उदारता और परस्पर सम्मान की भावना प्रदर्शित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह पड़ोसी राष्ट्रों के साथ सौहार्दपूर्ण और टिकाऊ संबंधों की नींव रखने के लिए एक रणनीतिक और कूटनीतिक आवश्यकता है।

153. (B) दक्षिण पूर्व एशिया संधि संगठन (SEATO)
शीत युद्ध के दौरान भारत ने सीटो जैसे सैन्य गठबंधनों का कड़ा विरोध किया क्योंकि वे क्षेत्र में गुटीय राजनीति और तनाव को बढ़ावा देते थे। भारत का मानना था कि ऐसे गठबंधन नव स्वतंत्र देशों की स्वायत्तता को सीमित करते हैं और उन्हें महाशक्तियों के संघर्ष का हिस्सा बना देते हैं। भारत ने इसके स्थान पर गुटनिरपेक्षता को प्राथमिकता दी ताकि वह अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन कर सके। सैन्य गुटों के प्रति भारत का यह विरोध क्षेत्रीय शांति और रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखने की उसकी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह राष्ट्रीय संप्रभुता और वैश्विक सुरक्षा के प्रति भारत के नैतिक दृष्टिकोण का प्रमाण था। भारत की यह नीति अंतरराष्ट्रीय संबंधों में महाशक्तियों के प्रभुत्व को संतुलित करने और विकासशील राष्ट्रों के सामूहिक हितों की रक्षा करने की दिशा में एक साहसिक और महत्वपूर्ण कूटनीतिक पहल थी।

154. (C) निर्भरता सिद्धांत
निर्भरता सिद्धांत यह तर्क देता है कि विकासशील देशों की आर्थिक संरचनाएं विकसित राष्ट्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाई गई हैं। इस सिद्धांत के अनुसार, परिधि के राष्ट्र अपनी तकनीक और पूंजी की जरूरतों के लिए हमेशा केंद्र पर निर्भर रहते हैं। यह निर्भरता उन्हें एक ऐसे चक्र में फंसा देती है जहाँ उनकी प्रगति केंद्र की समृद्धि के अधीन हो जाती है। यह अवधारणा वैश्विक व्यापार में मौजूद असमान शक्ति संबंधों को उजागर करती है और बताती है कि कैसे आर्थिक पिछड़ापन जानबूझकर कायम रखा जाता है। यह अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंधों में मौजूद संरचनात्मक बाधाओं और शोषणकारी प्रवृत्तियों का गहराई से विश्लेषण करता है। यह सिद्धांत वैश्विक अर्थव्यवस्था में समानता और न्याय सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक आर्थिक शासन के ढांचे में मौलिक सुधार की आवश्यकता पर बल देता है। यह विकासशील राष्ट्रों की आर्थिक स्वायत्तता के संघर्ष को प्रतिबिंबित करता है।

155. (A) केवल 3
दक्षिण-दक्षिण सहयोग विकासशील राष्ट्रों के बीच आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण ढांचा है। यह राष्ट्रों की सामूहिक आत्मनिर्भरता को मजबूत करने पर बल देता है। इसके विपरीत, एनआईईओ का प्रस्ताव विकासशील देशों द्वारा वैश्विक आर्थिक सुधार की मांग के रूप में रखा गया था, न कि विकसित देशों द्वारा। उत्तर-दक्षिण संवाद का अर्थ केवल भौगोलिक उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध नहीं, बल्कि अमीर और गरीब राष्ट्रों के बीच की वार्ता से है। अतः, केवल दक्षिण-दक्षिण सहयोग संबंधी कथन ही सटीक है। यह विकासशील राष्ट्रों के बीच एकजुटता और समानता पर आधारित एक महत्वपूर्ण साझेदारी को दर्शाता है। यह सहयोग वैश्विक विकास के लिए एक नई और न्यायपूर्ण दिशा प्रदान करने का प्रयास करता है। यह विकासशील राष्ट्रों की सामूहिक शक्ति और उनकी स्वायत्तता को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुदृढ़ करने का एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक प्रयास है।

156. (C) दक्षिणी राज्यों के बीच औपनिवेशिक निर्भरता की एक नई प्रणाली बनाना।
दक्षिण-दक्षिण सहयोग का मुख्य उद्देश्य उपनिवेशवाद के अवशेषों को समाप्त करना और विकासशील देशों के बीच बराबरी की साझेदारी स्थापित करना है। यह सहयोग सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने और अंतरराष्ट्रीय वार्ताओं में इन देशों की सामूहिक स्थिति को मजबूत करने पर केंद्रित है। इसमें ज्ञान, तकनीक और अनुभवों का आदान-प्रदान शामिल होता है ताकि आपसी विकास सुनिश्चित हो सके। निर्भरता की किसी भी नई प्रणाली का निर्माण करना इसके मूल सिद्धांतों और लक्ष्यों के पूर्णतः विरुद्ध है, क्योंकि यह राष्ट्रों की संप्रभुता का सम्मान करता है। यह विकासशील देशों के बीच विश्वास और एकजुटता को सुदृढ़ करने की दिशा में एक सकारात्मक पहल है। यह अंतरराष्ट्रीय आर्थिक शासन में समानता और न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में विकासशील देशों की साझा आकांक्षाओं और उनके संगठित प्रयासों का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। यह वैश्विक सहयोग का एक नवीन मॉडल है।

157. (B) यह अधिक सुव्यवस्थित और कानूनी रूप से बाध्यकारी प्रक्रिया की अनुमति देता है।
विश्व व्यापार संगठन का विवाद निपटान तंत्र गेट प्रणाली की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली और प्रभावी है। इसके निर्णय सदस्य देशों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होते हैं, जिससे अंतरराष्ट्रीय व्यापार नियमों का पालन सुनिश्चित होता है। इसमें एक निश्चित समय सीमा के भीतर विवादों को सुलझाने की व्यवस्था है, जो व्यापारिक अनिश्चितता को कम करती है। यह तंत्र किसी भी देश को एकपक्षीय कार्रवाई करने से रोकता है और छोटे राष्ट्रों को भी शक्तिशाली व्यापारिक साझेदारों के विरुद्ध न्याय प्राप्त करने का एक निष्पक्ष मंच प्रदान करता है। यह बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली में विश्वास बनाए रखने और व्यापारिक विवादों के समाधान के लिए एक अनिवार्य कानूनी

Click Here to Buy book on Amazon

आधार बने हुए हैं और वैश्विक स्तर पर संप्रभु समानता और न्यायसंगत अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की वकालत करते हैं।

170. (A) P-3, Q-4, R-1, S-2
विदेश नीति और कूटनीति अंतरराष्ट्रीय संबंधों के संचालन के दो अभिन्न पहलू हैं। विदेश नीति वह व्यापक रणनीति है जो किसी देश के बाहरी संबंधों को दिशा प्रदान करती है। कूटनीति उस रणनीति को बातचीत और संवाद के माध्यम से धरातल पर लागू करने का व्यावहारिक अभ्यास है। सुरक्षा समझौते राष्ट्रों के बीच आपसी रक्षा के लिए औपचारिक प्रतिबद्धताएं होती हैं। मध्यस्थ भूमिका तब देखी जाती है जब कोई देश संघर्षरत पक्षों के बीच सुलह कराने का प्रयास करता है। ये सभी तत्व मिलकर एक सुव्यवस्थित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का निर्माण करते हैं। यह अंतरराष्ट्रीय संबंधों की जटिलताओं को प्रबंधित करने और राष्ट्रहितों के साथ वैश्विक लक्ष्यों के बीच तालमेल बनाने के विभिन्न साधनों को स्पष्ट करता है। प्रभावी विदेश नीति और कुशल कूटनीति मिलकर ही किसी राष्ट्र के वैश्विक प्रभाव और उसकी सुरक्षा को सुदृढ़ करने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं।

171. (B) निकटतम दक्षिण एशियाई क्षेत्र के देशों के साथ संबंध।
'पड़ोसी पहले' नीति भारत की विदेश नीति की एक आधारशिला है, जो दक्षिण एशियाई क्षेत्र में स्थिरता और समृद्धि को प्राथमिकता देती है। भारत का मानना है कि उसके अपने विकास और सुरक्षा के लिए एक मजबूत और सहयोगी पड़ोस अनिवार्य है। इस नीति के तहत, भारत अपने पड़ोसियों के साथ व्यापार, कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे के विकास में सक्रिय भागीदारी करता है। यह दृष्टिकोण द्विपक्षीय विश्वास को मजबूत करने और क्षेत्रीय चुनौतियों का मिलकर सामना करने के लिए एक विश्वसनीय और प्रभावी ढांचा प्रदान करने का प्रयास करता है। यह दक्षिण एशियाई राष्ट्रों के बीच आपसी सहयोग और सौहार्दपूर्ण संबंधों को नया आयाम प्रदान करने का एक प्रभावी माध्यम है। भारत की यह नीति क्षेत्रीय स्थिरता और आर्थिक उत्थान के प्रति उसकी गंभीर प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जो राष्ट्रहितों और क्षेत्रीय एकीकरण के सफल समन्वय पर आधारित है।

172. (A) संयुक्त राष्ट्र की स्थापना संधि में संशोधन करना।
चार्टर संशोधन का तात्पर्य संयुक्त राष्ट्र के संविधान में परिवर्तन करने की औपचारिक प्रक्रिया से है। इसमें संगठन की संरचना, अंगों की शक्तियों या सदस्यता के नियमों में बदलाव शामिल हो सकता है। यह एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है जिसके लिए महासभा के दो-तिहाई बहुमत और सुरक्षा परिषद के सभी स्थाई सदस्यों की सहमति अनिवार्य होती है। चार्टर में संशोधन की मांग अक्सर सुरक्षा परिषद को अधिक लोकतांत्रिक बनाने के लिए की जाती है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि संगठन का मूल ढांचा केवल व्यापक अंतरराष्ट्रीय सहमति से ही बदला जाए। यह संगठन के भीतर संवैधानिक सुधार और वर्तमान वैश्विक वास्तविकताओं के अनुरूप इसके विकास की राह में एक स्थाई और चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया है। चार्टर में संशोधन के बिना संयुक्त राष्ट्र की लोकतांत्रिक वैधता और उसकी वैश्विक स्वीकार्यता को सुदृढ़ करना संभव नहीं है।

173. (B) आर्थिक-विकास
उत्तर-दक्षिण संवाद का मुख्य केंद्र बिंदु दुनिया के विकसित और विकासशील देशों के बीच मौजूद आर्थिक असमानता है। यह संवाद संसाधनों के न्यायसंगत वितरण, निष्पक्ष व्यापार नियमों और विकास सहायता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर केंद्रित रहता है। इसका उद्देश्य एक ऐसी वैश्विक व्यवस्था बनाना है जो निर्धन राष्ट्रों को विकास के समान अवसर प्रदान कर सके। यद्यपि इसमें राजनीतिक पहलू भी शामिल होते हैं, परंतु इसका मूल आधार सदैव आर्थिक न्याय और गरीबी उन्मूलन रहा है। यह संवाद वैश्विक समृद्धि के असंतुलन को दूर करने का एक संगठित प्रयास है। यह अंतरराष्ट्रीय आर्थिक शासन में समानता और न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में विकासशील देशों की साझा आकांक्षाओं और उनके संगठित कूटनीतिक प्रयासों का प्रतिबिंब है। यह वैश्विक सहयोग और सामूहिक समृद्धि की दिशा में एक महत्वपूर्ण और निरंतर चलने वाली ऐतिहासिक प्रक्रिया है।

174. (B) भारत-ब्राजील-दक्षिण अफ्रीका (IBSA) संवाद मंच।
इब्सा मंच दक्षिण-दक्षिण सहयोग का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जहाँ तीन अलग-अलग महाद्वीपों के प्रमुख लोकतंत्र एक साथ आते हैं। यह मंच विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाने, गरीबी कम करने और वैश्विक शासन में सुधार की मांग करने के लिए बनाया गया है। इसमें शामिल देश अपने अनुभवों और तकनीकी विशेषज्ञता को एक-दूसरे के साथ साझा करते हैं। यह सहयोग विकसित देशों पर निर्भरता को कम करने और वैश्विक दक्षिण की सामूहिक आवाज को सशक्त बनाने की दिशा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावी कूटनीतिक पहल है। यह राष्ट्रों के बीच समानता और परस्पर सम्मान के सिद्धांतों पर आधारित है, जो वैश्विक विकास के लिए एक नई और न्यायपूर्ण दिशा प्रदान करता है। इब्सा की सफलता दक्षिण-दक्षिण सहयोग की प्रासंगिकता और विकासशील राष्ट्रों की सामूहिक शक्ति को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुदृढ़ करने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को स्पष्ट रूप से दर्शाती है।

175. (B) आयातित वस्तुओं के बाजार में प्रवेश करने के पश्चात, उनके साथ घरेलू रूप से उत्पादित वस्तुओं की तुलना में कम अनुकूल व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए।
'राष्ट्रीय व्यवहार' का सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि विदेशी उत्पादों के साथ स्थानीय बाजार में कोई भेदभाव न हो। एक बार जब कोई आयातित वस्तु देश के भीतर प्रवेश कर लेती है, तो उस पर लगने वाले कर और नियम वही होने चाहिए जो घरेलू वस्तुओं पर लागू होते हैं। यह नियम स्थानीय उद्योगों को अनुचित लाभ लेने से रोकता है और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है। विश्व व्यापार संगठन का यह सिद्धांत अंतरराष्ट्रीय व्यापार में पारदर्शिता लाने और उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण विकल्प प्रदान करने के लिए एक अनिवार्य शर्त माना जाता है। यह बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली में विश्वास बनाए रखने और व्यापारिक बाधाओं को दूर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कानूनी और नीतिगत सुधार है। यह वैश्विक बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा और समानता सुनिश्चित करने की दिशा

NODIA

आधार बने हुए हैं। यह वैश्विक अर्थव्यवस्था की जटिलताओं को हल करने और वित्तीय संकटों को रोकने के लिए दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच एक प्रभावी नीतिगत समन्वय सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण मंच है। यह वर्तमान वैश्विक आर्थिक शासन में उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं की निर्णायक भूमिका को स्पष्ट करता है।

140. (C) द्विपक्षीय राजनीतिक संघर्षों का व्यापक प्रभाव।
सार्क की सफलता में सबसे बड़ी बाधा इसके सदस्य देशों के बीच मौजूद अनसुलझे द्विपक्षीय विवाद रहे हैं। विशेष रूप से भारत और पाकिस्तान के बीच के तनावपूर्ण संबंधों ने अक्सर संगठन की कार्यप्रणाली को प्रभावित किया है। इन राजनीतिक मतभेदों के कारण क्षेत्रीय व्यापार और सहयोग की कई महत्वपूर्ण योजनाएं प्रभावी ढंग से लागू नहीं हो सकीं। सार्क चार्टर में द्विपक्षीय मुद्दों को न उठाने का प्रावधान होने के बावजूद, इनका परोक्ष प्रभाव संगठन की प्रगति और इसकी निर्णय लेने की क्षमता को सीमित करता रहा है। यह क्षेत्रीय सहयोग की राह में एक महत्वपूर्ण चुनौती और बाधा बनी हुई है। दक्षिण एशियाई क्षेत्र के समग्र विकास और एकीकरण के लिए इन द्विपक्षीय तनावों को कम करना और परस्पर विश्वास बहाल करना अनिवार्य है। यह संगठन की भविष्य की प्रासंगिकता के लिए एक निर्णायक कारक है।

141. (A) तेल बाजारों को विनियमित और स्थिर करना।
ओपेक का मुख्य उद्देश्य तेल उत्पादक देशों के बीच पेट्रोलियम नीतियों का समन्वय करना है ताकि वैश्विक तेल बाजार में स्थिरता बनी रहे। यह संगठन आपूर्ति की मात्रा निर्धारित करके कीमतों को अत्यधिक उतार-चढ़ाव से बचाने का प्रयास करता है। इसका लक्ष्य उत्पादक राष्ट्रों के लिए उचित आय सुनिश्चित करना और उपभोक्ता देशों के लिए तेल की निरंतर आपूर्ति बनाए रखना है। ओपेक की नीतियां विश्व की ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक अर्थव्यवस्था के सुचारु संचालन में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावी भूमिका निभाती हैं। यह प्राकृतिक संसाधनों पर संप्रभुता प्राप्त करने और अंतरराष्ट्रीय बाजार में उत्पादकों के हितों की रक्षा करने की दिशा में एक संगठित प्रयास है। यह वैश्विक ऊर्जा राजनीति में विकासशील देशों की शक्ति और उनके सामूहिक प्रभाव को सुदृढ़ करता है। यह अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंधों में तेल की महत्ता को रेखांकित करता है।

142. (A) "महाशक्ति एकमतता" (Great power unanimity)
सुरक्षा परिषद में वीटो शक्ति को तकनीकी रूप से "महाशक्ति एकमतता" के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। इसका अर्थ है कि किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय के लिए सभी पांच स्थाई सदस्यों की सहमति आवश्यक है। यदि एक भी स्थाई सदस्य प्रस्ताव के विरुद्ध मत देता है, तो वह प्रस्ताव गिर जाता है। यह सिद्धांत इस धारणा पर आधारित है कि अंतरराष्ट्रीय शांति तभी बनी रह सकती है जब प्रमुख विश्व शक्तियां मिलकर कार्य करें। यह वीटो शक्ति सुरक्षा परिषद की निर्णय लेने की प्रक्रिया का सबसे विवादास्पद हिस्सा है। यह अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और संघर्ष प्रबंधन की संरचना में महाशक्तियों के निर्णायक प्रभाव और उनकी विशेष जिम्मेदारी को स्पष्ट रूप से उजागर करता है। यह संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के समय की ऐतिहासिक परिस्थितियों और उस समय के शक्ति संतुलन को प्रतिबिंबित करने वाला एक आधारभूत संवैधानिक प्रावधान है।

143. (D) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।
संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव आमतौर पर सदस्य देशों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होते, बल्कि वे अंतरराष्ट्रीय राय और नैतिक दबाव का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके विपरीत, सुरक्षा परिषद के पास प्रवर्तन शक्तियां होती हैं जिनके निर्णय बाध्यकारी हो सकते हैं। महासभा का वास्तविक महत्व यह है कि यह दुनिया के सभी राष्ट्रों को अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर खुलकर चर्चा करने के लिए एक अद्वितीय और सार्वभौमिक मंच प्रदान करती है। यहाँ प्रत्येक देश को अपनी बात रखने और वैश्विक एजेंडा को प्रभावित करने का समान अवसर मिलता है। यह संगठन के भीतर लोकतांत्रिक समावेशिता और संप्रभु समानता के सिद्धांतों को सुदृढ़ करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। यद्यपि इसके निर्णय कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं हैं, परंतु उनकी वैश्विक स्वीकृति और नैतिक शक्ति अंतरराष्ट्रीय राजनीति और मानदंडों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

144. (C) आर्थिक अभाव और संघर्ष के बीच एक मान्यता प्राप्त संबंध है।
संयुक्त राष्ट्र की कार्यप्रणाली इस विचार पर आधारित है कि गरीबी, बेरोजगारी और आर्थिक असमानता अक्सर सामाजिक अस्थिरता और संघर्षों को जन्म देती हैं। इसलिए, स्थाई शांति स्थापित करने के लिए विकास के मुद्दों को हल करना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। संगठन के शांति स्थापना अभियानों में अब अक्सर पुनर्निर्माण और मानवीय सहायता जैसे विकास संबंधी तत्व शामिल होते हैं। यह एकीकृत दृष्टिकोण मानता है कि सुरक्षा और आर्थिक समृद्धि एक ही प्रक्रिया के दो अविभाज्य हिस्से हैं, जो एक-दूसरे को सुदृढ़ करते हैं। यह अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए एक समग्र और दीर्घकालिक समाधान प्रस्तुत करता है। यह विकासशील राष्ट्रों के आर्थिक उत्थान और सामाजिक न्याय को वैश्विक स्थिरता की आधारशिला के रूप में मान्यता प्रदान करता है। यह संयुक्त राष्ट्र के लक्ष्यों और उसके व्यापक मानवीय दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है।

145. (B) एन एजेंडा फॉर पीस (An Agenda for Peace)
'एन एजेंडा फॉर पीस' रिपोर्ट में शांति स्थापना, शांति निर्माण और शांति सुदृढ़ीकरण की अवधारणाओं को बहुत ही विस्तार और स्पष्टता से परिभाषित किया गया था। इस दस्तावेज ने बताया कि कैसे संयुक्त राष्ट्र न केवल युद्धों को रोक सकता है, बल्कि संघर्ष के मूल कारणों को हल करके स्थाई शांति भी कायम कर सकता है। इसने निवारक कूटनीति और युद्ध के बाद के पुनर्निर्माण कार्यों पर विशेष बल दिया। यह रिपोर्ट आज भी संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक शांति प्रयासों के लिए एक आधारभूत नीतिगत मार्गदर्शिका मानी जाती है। यह अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और संघर्ष प्रबंधन की दिशा में संगठन की क्षमताओं को मजबूत करने और उसे नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करने का एक ऐतिहासिक प्रयास था। इसने समकालीन शांति

Downloaded from www.pdf.tube

माध्यम है। यह क्षेत्रीय विकास के लिए शिक्षा और शोध की महत्ता को रेखांकित करता है। यह सार्क के लक्ष्यों और उसके व्यापक क्षेत्रीय सहयोग के दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करने वाली एक महत्वपूर्ण संस्थागत उपलब्धि है।

182. (C) एक उत्पादक संघ (कार्टेल)।
ओपेक की तेल कीमतों को प्रभावित करने की शक्ति इस तथ्य में निहित है कि यह प्रमुख तेल निर्यातक देशों का एक संगठित समूह है। एक कार्टेल के रूप में कार्य करते हुए, यह सदस्य देशों के उत्पादन को नियंत्रित करता है ताकि वैश्विक बाजार में आपूर्ति और मांग का संतुलन बना रहे। जब ओपेक उत्पादन में कटौती का निर्णय लेता है, तो वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतें बढ़ जाती हैं। यह शक्ति ओपेक को वैश्विक ऊर्जा राजनीति और विश्व की आर्थिक स्थिरता को प्रभावित करने वाला एक अत्यंत शक्तिशाली और निर्णायक खिलाड़ी बनाती है। यह प्राकृतिक संसाधनों पर संप्रभु नियंत्रण और अंतरराष्ट्रीय बाजार में उत्पादकों के सामूहिक हितों की रक्षा का प्रतीक है। ओपेक की नीतियां विश्व की ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक अर्थव्यवस्था के सुचारू संचालन में एक महत्वपूर्ण और प्रभावी भूमिका निभाती हैं। यह अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंधों में तेल की निर्णायक महत्ता को उजागर करता है।

183. (A) 'A' और 'R' दोनों सही हैं और 'R', 'A' की सही व्याख्या है।
अमेरिकी राज्यों के संगठन को अक्सर इस आलोचना का सामना करना पड़ता है कि यह संयुक्त राज्य अमेरिका के हितों से बहुत अधिक प्रभावित है। चूंकि इसका मुख्यालय वाशिंगटन में है और अमेरिका इसका सबसे बड़ा वित्तीय स्रोत है, इसलिए इसके निर्णयों पर अमेरिकी प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। कई लैटिन अमेरिकी देशों ने समय-समय पर संगठन की निष्पक्षता और इसकी स्वायत्तता पर प्रश्न उठाए हैं। यह स्थिति संगठन के भीतर शक्ति के असंतुलन और सदस्य राष्ट्रों के बीच विश्वास की कमी को उजागर करती है, जो इसकी कार्यक्षमता को प्रभावित करती है। यह क्षेत्रीय सहयोग की राह में एक महत्वपूर्ण चुनौती और ऐतिहासिक प्रभाव का मुद्दा बना हुआ है। क्षेत्रीय अखंडता और समानता सुनिश्चित करने के लिए संगठन के भीतर शक्ति का संतुलित वितरण और सदस्य राष्ट्रों के बीच परस्पर विश्वास बहाल करना अनिवार्य है। यह ओएएस की भविष्य की प्रासंगिकता के लिए एक निर्णायक कारक है।

184. (C) 1945
संयुक्त राष्ट्र की स्थापना आधिकारिक रूप से 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, जो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के ठीक बाद का समय था। इसका मुख्य उद्देश्य दुनिया को भविष्य के भीषण युद्धों से बचाना और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना था। 51 संस्थापक देशों ने इसके चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें भारत भी शामिल था। यह संगठन राष्ट्र संघ की विफलताओं से सीख लेकर बनाया गया था ताकि एक अधिक प्रभावी वैश्विक सुरक्षा प्रणाली स्थापित की जा सके। तब से यह अंतरराष्ट्रीय शांति और न्याय के लिए सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण वैश्विक मंच बना हुआ है। यह वैश्विक शासन की आधारशिला और अंतरराष्ट्रीय सहयोग का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है। इसकी स्थापना मानवता के बेहतर और सुरक्षित भविष्य के लिए एक वैश्विक संकल्प का प्रतीक थी। यह संगठन आज भी अंतरराष्ट्रीय राजनीति और सुरक्षा प्रबंधन में एक निर्णायक और अपरिहार्य भूमिका निभाता है।

185. (C) कोरियाई युद्ध
कोरियाई युद्ध के दौरान सुरक्षा परिषद के स्थाई सदस्यों के बीच गहरे मतभेद उत्पन्न हो गए थे, जिससे परिषद पंगु हो गई थी। इसी गतिरोध को दूर करने के लिए 1950 में "शांति के लिए एकता" प्रस्ताव लाया गया था। इस प्रस्ताव ने महासभा को यह शक्ति दी कि यदि सुरक्षा परिषद शांति बनाए रखने में विफल रहती है, तो महासभा स्वयं कार्रवाई कर सकती है। यह संयुक्त राष्ट्र के इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ था जिसने संगठन की कार्यप्रणाली में लचीलापन और संकट के समय निर्णय लेने की वैकल्पिक क्षमता को जन्म दिया। यह अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में महासभा की भूमिका को सुदृढ़ करता है और महाशक्तियों के वीटो के कारण होने वाले गतिरोध को दूर करने का एक प्रभावी मार्ग प्रदान करता है। यह वैश्विक सुरक्षा और शांति स्थापना की दिशा में संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों की अनुकूलन क्षमता और उसकी प्रशासनिक सूझबूझ का एक ऐतिहासिक प्रमाण है।

186. (C) इसका प्रदर्शन मिश्रित रहा है, सामाजिक/मानवीय क्षेत्रों में उल्लेखनीय सफलताओं के साथ लेकिन शांति और सुरक्षा बनाए रखने में चुनौतियों के साथ।
संयुक्त राष्ट्र का मूल्यांकन करने पर स्पष्ट होता है कि इसने स्वास्थ्य, शिक्षा और मानवाधिकारों जैसे क्षेत्रों में अत्यंत सराहनीय कार्य किया है। चेचक जैसी बीमारियों का उन्मूलन और करोड़ों लोगों तक मानवीय सहायता पहुँचाना इसकी बड़ी उपलब्धियां हैं। हालांकि, बड़े वैश्विक संघर्षों को रोकने और शक्तिशाली देशों के एकपक्षीय निर्णयों पर लगाम लगाने में इसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। अतः, इसकी सफलता और विफलता का संतुलन मिश्रित है, जहाँ यह एक ओर अत्यंत आवश्यक है, वहीं दूसरी ओर इसमें सुधार की व्यापक संभावनाएं भी मौजूद हैं। यह संगठन की वैश्विक प्रासंगिकता और उसकी प्रभावशीलता को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर सुधार और लोकतांत्रिक बदलाव की आवश्यकता को रेखांकित करता है। यह अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के साथ-साथ मानवीय कल्याण की दिशा में संयुक्त राष्ट्र की व्यापक और जटिल भूमिका को स्पष्ट रूप से उजागर करता है।

187. (B) सुरक्षा परिषद के P5 सदस्य बड़ा हिस्सा देते हैं।
संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना अभियानों का वित्तपोषण सदस्य देशों की आर्थिक क्षमता के आधार पर किया जाता है। एक विशेष सूत्र के अनुसार, सुरक्षा परिषद के पांच स्थाई सदस्य, जिन्हें अंतरराष्ट्रीय शांति की प्राथमिक जिम्मेदारी दी गई है, शांति अभियानों के खर्च का एक बड़ा और अनिवार्य हिस्सा वहन करते हैं। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि वैश्विक सुरक्षा के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध रहें और धनी राष्ट्र अपनी जिम्मेदारी निभाएं। यह संगठन की उन वित्तीय नीतियों का हिस्सा है जो शांति बनाए रखने के लिए सामूहिक वित्तीय प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। यह अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा

NODIA

में एक प्रभावी तंत्र प्रदान करता है जो अंतरराष्ट्रीय वाणिज्य के सुचारु संचालन में सहायक है।

176. (C) वैश्वीकरण और आर्थिक अन्योन्याश्रयता का उदय।
अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था एक विषय के रूप में तब और अधिक महत्वपूर्ण हुई जब राष्ट्रों के बीच आर्थिक निर्भरता बढ़ने लगी। वैश्वीकरण ने यह स्पष्ट कर दिया कि राजनीतिक निर्णय और आर्थिक गतिविधियां एक-दूसरे से अलग नहीं रह सकतीं। व्यापारिक संबंधों और वित्तीय प्रवाहों ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति की दिशा को गहराई से प्रभावित किया है। इस क्षेत्र का अध्ययन अब यह समझने के लिए अनिवार्य हो गया है कि वैश्विक बाजार और राज्य की शक्ति कैसे एक-दूसरे को आकार देते हैं। यह बदलते हुए विश्व की जटिलताओं का विश्लेषण करने का एक प्रभावी माध्यम है। यह अंतरराष्ट्रीय संबंधों के वास्तविक आधारों का तार्किक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। यह राष्ट्रों की संप्रभुता और वैश्विक आर्थिक शासन के बीच के जटिल अंतर्संबंधों को स्पष्ट करने वाला एक महत्वपूर्ण सैद्धांतिक और व्यावहारिक दृष्टिकोण है जो वर्तमान वैश्विक व्यवस्था को समझने के लिए अनिवार्य है।

177. (B) निर्भरता सिद्धांत
जब कोई देश केवल कच्चे माल के निर्यात पर निर्भर रहता है और अपनी अधिकांश आवश्यकताओं के लिए आयात करता है, तो वह निर्भरता की स्थिति में होता है। यह स्थिति उसे वैश्विक बाजार के उतार-चढ़ाव के प्रति संवेदनशील बनाती है और उसके औद्योगिक विकास को बाधित करती है। निर्भरता सिद्धांत के अनुसार, यह संरचनात्मक ढांचा विकसित राष्ट्रों को लाभ पहुँचाने के लिए बनाया गया है। ऐसे देश अक्सर आर्थिक कर्ज के जाल में फंस जाते हैं और उनकी संप्रभुता सीमित हो जाती है। यह वैश्विक अर्थव्यवस्था में मौजूद शक्ति के असंतुलन और शोषणकारी प्रवृत्तियों का गहराई से विश्लेषण करता है। यह सिद्धांत वैश्विक स्तर पर धन और शक्ति के असमान वितरण के ऐतिहासिक और संरचनात्मक कारणों को उजागर करता है। यह विकासशील राष्ट्रों की आर्थिक स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक आर्थिक शासन के ढांचे में मौलिक सुधार की आवश्यकता पर बल देने वाला एक महत्वपूर्ण सैद्धांतिक ढांचा प्रस्तुत करता है।

178. (A) 2, 1, 4, 3
विकासशील देशों के आंदोलनों का कालक्रम उनकी एकजुटता के विकास को दर्शाता है। 1955 का बांडुंग सम्मेलन इसकी पहली प्रमुख कड़ी था। इसके पश्चात 1961 में बेलग्रेड में पहला गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। 1964 में विकासशील देशों ने अपने आर्थिक हितों की रक्षा के लिए जी-77 का गठन किया। अंत में, 1973 के अल्जीयर्स शिखर सम्मेलन में नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की औपचारिक मांग की गई। यह क्रम दर्शाता है कि कैसे राजनीतिक स्वतंत्रता के बाद आर्थिक स्वायत्तता की दिशा में प्रयास संगठित और मुखर हुए। यह वैश्विक सहयोग के इतिहास में विकासशील राष्ट्रों के सामूहिक संघर्ष और उनके स्वाभिमान का प्रतीक है। यह अंतरराष्ट्रीय संबंधों में एक नए और न्यायपूर्ण वैश्विक दृष्टिकोण के क्रमिक विकास का मार्ग प्रशस्त करने वाले महत्वपूर्ण ऐतिहासिक मील के पत्थरों को तार्किक और व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करता है।

179. (B) आसियान शैली (ASEAN Way)
आसियान के भीतर सहयोग और निर्णय लेने की अनूठी पद्धति को 'आसियान शैली' के रूप में पहचाना जाता है। यह पद्धति सदस्य देशों के बीच आम सहमति बनाने और एक-दूसरे के आंतरिक मामलों में अहस्तक्षेप करने पर आधारित है। इसमें औपचारिक और कानूनी समझौतों के बजाय अनौपचारिक परामर्श और आपसी समझ को अधिक महत्व दिया जाता है। यह दृष्टिकोण क्षेत्र में मौजूद विविध राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रणालियों के बावजूद शांति और स्थिरता बनाए रखने में सफल रहा है। यह एशियाई कूटनीति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रभावशाली मॉडल माना जाता है। यह क्षेत्रीय स्थिरता और परस्पर सहयोग की एक सफल और अद्वितीय एशियाई पद्धति को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। यह विविधतापूर्ण प्रणालियों के बावजूद राष्ट्रों को एक साथ लाने और उनमें सहयोग की भावना विकसित करने में अत्यंत सहायक सिद्ध हुई है। यह क्षेत्रीय एकीकरण का एक सशक्त उदाहरण है।

180. (C) इसकी अध्यक्षता वार्षिक रूप से इसके सदस्यों के बीच बदलती रहती है।
जी-20 की अध्यक्षता प्रत्येक वर्ष एक सदस्य देश से दूसरे सदस्य देश को हस्तांतरित होती है, जो इसकी चक्रीय नेतृत्व संरचना को दर्शाता है। यह प्रणाली सुनिश्चित करती है कि विभिन्न क्षेत्रों और अर्थव्यवस्थाओं को वैश्विक एजेंडा निर्धारित करने का समान अवसर मिले। जिस देश के पास अध्यक्षता होती है, वह शिखर सम्मेलन की मेजबानी करता है और मुख्य प्राथमिकताओं को तय करता है। इसका कोई स्थाई सचिवालय नहीं है, बल्कि 'ट्रोइका' प्रणाली के माध्यम से निरंतरता बनी रहती है। यह लचीलापन जी-20 को एक गतिशील और समावेशी अंतरराष्ट्रीय मंच बनाने में सहायक होता है। यह वैश्विक आर्थिक शासन में लोकतांत्रिक भागीदारी और समावेशिता सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। जी-20 की यह अनूठी नेतृत्व संरचना इसके निर्णयों की वैश्विक स्वीकार्यता और इसके नीतिगत समन्वय की प्रभावशीलता को सुदृढ़ करने में एक निर्णायक भूमिका निभाती है।

181. (C) सार्क (SAARC)
दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय सार्क की एक महत्वपूर्ण और दूरदर्शी पहल है जिसका उद्देश्य क्षेत्र के युवाओं के बीच शैक्षणिक और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना है। नई दिल्ली में स्थित यह संस्थान दक्षिण एशिया के विभिन्न देशों के छात्रों को एक साझा मंच प्रदान करता है जहाँ वे मिलकर ज्ञान अर्जित कर सकें। यह पहल क्षेत्रीय एकीकरण और आपसी समझ विकसित करने की दिशा में एक मजबूत कदम है। इसके माध्यम से सार्क सदस्य देशों के बीच बौद्धिक संबंधों को सुदृढ़ करने और क्षेत्र की साझा चुनौतियों के समाधान खोजने का प्रयास करता है। यह दक्षिण एशियाई राष्ट्रों के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण

Click Here to Buy book on Amazon

पश्चिमी गोलार्ध में उत्तर अमेरिकी और लैटिन अमेरिकी देशों के एकीकरण और सहयोग का प्रमुख मंच बना हुआ है। ये सभी तत्व वैश्विक शासन और क्षेत्रीय सहयोग के बदलते स्वरूप को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण आधार प्रदान करते हैं। ये अवधारणाएं राष्ट्रों के बीच आर्थिक और सुरक्षा संबंधों को प्रबंधित करने के विभिन्न साधनों और ऐतिहासिक मील के पत्थरों को स्पष्ट करती हैं। यह अंतरराष्ट्रीय कूटनीति और क्षेत्रीय एकीकरण के प्रयासों के क्रमिक विकास और उनकी वर्तमान प्रासंगिकता का एक व्यवस्थित सारांश प्रस्तुत करता है।

194. (A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
नव-उपनिवेशवाद उस स्थिति का वर्णन करता है जहाँ पूर्व उपनिवेश राजनीतिक रूप से स्वतंत्र होने के बाद भी आर्थिक रूप से विकसित देशों के नियंत्रण में रहते हैं। यह नियंत्रण ऋण, व्यापारिक शर्तों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के माध्यम से होता है। निर्भरता सिद्धांत इस प्रक्रिया को समझने के लिए एक मजबूत सैद्धांतिक ढांचा प्रदान करता है, जो यह बताता है कि कैसे संसाधनों का प्रवाह परिधि से केंद्र की ओर बना रहता है। ये दोनों अवधारणाएं मिलकर आधुनिक वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में मौजूद असमानता और शोषण के सूक्ष्म रूपों को स्पष्ट रूप से उजागर करती हैं। यह स्वतंत्र राष्ट्रों की आर्थिक संप्रभुता और उनके स्वावलंबन के संघर्ष को प्रतिबिंबित करता है। यह अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंधों के भीतर मौजूद संरचनात्मक बाधाओं और विकसित राष्ट्रों के अप्रत्यक्ष प्रभुत्व का गहराई से विश्लेषण करने वाला एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है। यह वैश्विक स्तर पर धन और शक्ति के असमान वितरण के ऐतिहासिक और वर्तमान कारणों को समझने के लिए अनिवार्य है।

195. (C) जिनेवा, स्विट्जरलैंड
विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में स्थित है, जो अंतरराष्ट्रीय कूटनीति और व्यापारिक वार्ताओं का एक प्रमुख केंद्र है। यह स्थान संगठन के सचिवालय और विभिन्न परिषदों की गतिविधियों के लिए एक स्थाई आधार प्रदान करता है। जिनेवा में मुख्यालय होने के कारण सदस्य राष्ट्रों के प्रतिनिधि यहाँ निरंतर व्यापारिक विवादों और नए समझौतों पर चर्चा करते हैं। यह शहर अपनी तटस्थता और वैश्विक संस्थानों की मेजबानी के लिए प्रसिद्ध है, जो डब्ल्यूटीओ के निष्पक्ष कार्यकरण के लिए एक आदर्श वातावरण तैयार करने में सहायक होता है। यह अंतरराष्ट्रीय वाणिज्य और बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के प्रबंधन के लिए एक महत्वपूर्ण संस्थागत केंद्र है। जिनेवा की कूटनीतिक महत्ता और डब्ल्यूटीओ की संरचनात्मक मजबूती मिलकर वैश्विक व्यापार नियमों के प्रभावी कार्यान्वयन और सदस्य देशों के बीच सुचारू संवाद सुनिश्चित करती है। यह अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंधों में पारदर्शिता और स्थिरता बनाए रखने का एक अनिवार्य आधार प्रदान करता है।

196. (B) ओपेक (OPEC)
"सामूहिक कार्रवाई का तर्क" ओपेक जैसे संगठनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जहाँ सदस्यों को अपने व्यक्तिगत लाभ के बजाय समूह के हितों के लिए उत्पादन में कटौती करनी पड़ती है। यह चुनौती तब उत्पन्न होती है जब कुछ सदस्य अधिक लाभ के लिए निर्धारित कोटा से अधिक उत्पादन करने का प्रयास करते हैं। यदि सभी सदस्य नियमों का पालन करते हैं, तो पूरा समूह तेल की कीमतों को नियंत्रित कर सकता है। यह सिद्धांत यह समझने में मदद करता है कि साझा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रों के बीच सहयोग बनाए रखना कितना कठिन और आवश्यक है। यह अंतरराष्ट्रीय संबंधों में सामूहिक शक्ति और सदस्य राष्ट्रों की व्यक्तिगत स्वार्थपरता के बीच के द्वंद्व को उजागर करता है। ओपेक की सफलता इसकी आंतरिक एकजुटता और उत्पादन नीतियों के प्रति सदस्यों की प्रतिबद्धता पर निर्भर करती है। यह वैश्विक ऊर्जा बाजार में स्थिरता बनाए रखने और उत्पादकों के हितों की रक्षा करने के लिए एक अनिवार्य रणनीतिक दृष्टिकोण है।

197. (B) बोगोटा, कोलंबिया
अमेरिकी राज्यों के संगठन के संस्थापक चार्टर पर 1948 में कोलंबिया की राजधानी बोगोटा में हस्ताक्षर किए गए थे, इसलिए इसे 'बोगोटा का चार्टर' भी कहा जाता है। यह ऐतिहासिक घटना पश्चिमी गोलार्ध के राष्ट्रों के बीच एक औपचारिक और स्थाई सहयोग की शुरुआत थी। इस चार्टर ने सदस्य देशों के अधिकारों और कर्तव्यों को परिभाषित किया और क्षेत्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने का संकल्प लिया। यह दस्तावेज आज भी संगठन की कानूनी आधारशिला बना हुआ है और अमेरिकी महाद्वीप के देशों के बीच एकजुटता और न्याय को बढ़ावा देता है। यह क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक मील का पत्थर है। बोगोटा चार्टर की महत्ता इसके द्वारा स्थापित क्षेत्रीय सहयोग के व्यापक और समावेशी ढांचे में निहित है, जो पश्चिमी गोलार्ध के राष्ट्रों के बीच कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करने और सामूहिक चुनौतियों का सामना करने के लिए एक स्थाई और सुदृढ़ आधार प्रदान करता है।

198. (B) 5 स्थाई और 10 अस्थाई होते हैं।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की संरचना में कुल 15 सदस्य राष्ट्र शामिल होते हैं। इनमें पांच स्थाई सदस्य हैं जिनके पास वीटो की विशेष शक्ति होती है, जबकि शेष 10 सदस्यों को महासभा द्वारा दो वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित किया जाता है। यह अस्थाई सदस्यता विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के बीच वितरित की जाती है ताकि दुनिया का उचित प्रतिनिधित्व हो सके। स्थाई सदस्य संगठन की निरंतरता सुनिश्चित करते हैं, जबकि अस्थाई सदस्य समय-समय पर नए दृष्टिकोण और क्षेत्रीय चिंताओं को सुरक्षा परिषद के एजेंडे में लाने का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। यह संरचना अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रबंधन में महाशक्तियों के निर्णायक प्रभाव और अन्य राष्ट्रों की भागीदारी के बीच एक संतुलन बनाने का प्रयास करती है। हालांकि सुरक्षा परिषद की वर्तमान संरचना में सुधार और विस्तार की मांग निरंतर बनी हुई है ताकि यह 21वीं सदी की भू-राजनीतिक वास्तविकताओं और लोकतांत्रिक मूल्यों को अधिक प्रभावी ढंग से प्रतिबिंबित कर सके।

Downloaded from www.pdf.tube

210. (A) P-2, Q-4, R-1, S-3
विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संगठन अपनी विशिष्ट विशेषताओं और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के माध्यम से वैश्विक व्यवस्था में अपना योगदान देते हैं। संयुक्त राष्ट्र चार्टर में समय-समय पर सुधार और संशोधन की मांग की जाती रही है। जी-20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए एक अनौपचारिक और प्रभावी मंच के रूप में कार्य करता है। ओपेक का प्राथमिक कार्य सदस्य देशों की पेट्रोलियम नीतियों का समन्वय करना है। सार्क की नींव ढाका शिखर सम्मेलन में रखी गई थी, जिसने दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग की औपचारिक शुरुआत की थी। ये सभी तत्व वैश्विक शासन और विकास की संरचना को निर्धारित करने वाले महत्वपूर्ण आधारभूत स्तंभ हैं। ये ऐतिहासिक दस्तावेज और संगठन अंतरराष्ट्रीय राजनीति और सुरक्षा प्रबंधन में एक निर्णायक और अपरिहार्य भूमिका निभाते हैं। यह अंतरराष्ट्रीय कूटनीति और क्षेत्रीय एकीकरण के प्रयासों के क्रमिक विकास और उनकी वर्तमान प्रासंगिकता को तार्किक और व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने वाला एक अनिवार्य ऐतिहासिक प्रमाण है।

211. (C) न्यास परिषद (Trusteeship Council)
न्यास परिषद की स्थापना उन क्षेत्रों के कल्याण और विकास के लिए की गई थी जो स्वशासन प्राप्त करने में सक्षम नहीं थे। इसका मुख्य उद्देश्य इन न्यास क्षेत्रों को स्वतंत्रता या स्वशासन की ओर ले जाना था। परिषद ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के वि-उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब अंतिम न्यास क्षेत्र ने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली, तो इस अंग ने अपनी सफलता के बाद अपने नियमित कार्यों को स्थगित कर दिया। यह संयुक्त राष्ट्र के उन अंगों का उदाहरण है जिसने अपने ऐतिहासिक मिशन को सफलतापूर्वक पूर्ण किया है। यह अंतरराष्ट्रीय वि-उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया में संयुक्त राष्ट्र की सफलता और उसकी ऐतिहासिक भूमिका का एक उत्कृष्ट प्रमाण है। संगठन ने अपने चार्टर द्वारा निर्धारित उद्देश्यों को पूर्णतः प्राप्त करके वैश्विक न्याय और स्वतंत्रता की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर स्थापित किया है। यह संयुक्त राष्ट्र के सुव्यवस्थित कार्यकरण और लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण संस्थागत उदाहरण है।

212. (B) सुरक्षा परिषद
सुरक्षा परिषद में शक्ति संघर्ष का सबसे मुख्य कारण वीटो शक्ति है, जो पांच स्थाई सदस्यों को किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय को रोकने का अधिकार देती है। यह शक्ति अक्सर परिषद को विभाजित कर देती है, विशेषकर जब स्थाई सदस्यों के राष्ट्रीय हित आपस में टकराते हैं। इस निषेधाधिकार के कारण कई अंतरराष्ट्रीय संकटों का समाधान नहीं हो पाता, जिससे संगठन की प्रभावशीलता पर प्रश्न उठते हैं। यह व्यवस्था परिषद के भीतर एक स्थाई शक्ति असंतुलन पैदा करती है, जो वर्तमान लोकतांत्रिक और बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था के पूर्णतः विपरीत मानी जाती है। सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग इसी विसंगति को दूर करने और इसे अधिक लोकतांत्रिक बनाने के लिए है। यह अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रबंधन में महाशक्तियों के निर्णायक प्रभाव और उनकी विशेष जिम्मेदारी को स्पष्ट रूप से उजागर करता है। सुधार के बिना संयुक्त राष्ट्र की लोकतांत्रिक वैधता और उसकी वैश्विक स्वीकार्यता को सुदृढ़ करना संभव नहीं है, जो वैश्विक न्याय की दिशा में एक अनिवार्य चुनौती है।

213. (B) संयुक्त राष्ट्र शांति सेना
"ब्लू हेलमेट" संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के लिए विश्व भर में उपयोग किया जाने वाला एक प्रसिद्ध और सम्मानजनक नाम है। यह नाम उनकी विशिष्ट नीली टोपियों और हेलमेटों से आया है, जो उन्हें किसी भी युद्ध क्षेत्र में एक निष्पक्ष शांति रक्षक के रूप में अलग पहचान देते हैं। ये सैनिक विभिन्न देशों की सेनाओं से आते हैं और संयुक्त राष्ट्र के झंडे तले अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बहाल करने का कठिन कार्य करते हैं। उनकी उपस्थिति संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में नागरिकों की रक्षा और शांति समझौतों को लागू करने का एक मजबूत आश्वासन होती है। शांति अभियानों की सफलता के लिए निष्पक्षता के साथ-साथ मेजबान राष्ट्र की सहमति और केवल आत्मरक्षा में बल प्रयोग की नीति का पालन करना अनिवार्य है। यह वैश्विक शांति स्थापना के मानवीय मिशन का एक आधारभूत और पवित्र स्तंभ है। शांति सैनिकों का यह त्याग और समर्पण अंतरराष्ट्रीय समुदाय के भीतर सामूहिक सुरक्षा और शांति के प्रति राष्ट्रों की साझा प्रतिबद्धता को स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित करता है।

214. (B) शीत युद्ध के शक्ति गुटों से दूर रहना।
गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना शीत युद्ध के दौरान हुई थी जब दुनिया दो विरोधी सैन्य गुटों में विभाजित थी। भारत और अन्य संस्थापक देशों का उद्देश्य अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करना और महाशक्तियों के संघर्ष का मोहरा बनने से बचना था। इस आंदोलन ने नव स्वतंत्र राष्ट्रों को अपनी स्वायत्तता बनाए रखने और अपनी विकास प्राथमिकताओं के अनुसार निर्णय लेने का एक स्वतंत्र मंच प्रदान किया। यह केवल अलगाववाद नहीं था, बल्कि वैश्विक शांति और न्याय के लिए एक सक्रिय और नैतिक कूटनीतिक प्रयास था। इसने अंतरराष्ट्रीय संबंधों में एक नए और न्यायपूर्ण वैश्विक दृष्टिकोण के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। गुटनिरपेक्षता की नीति ने विकासशील राष्ट्रों को अपनी संप्रभुता सुरक्षित रखने और महाशक्तियों के दबाव से बचने के लिए एक साझा मंच प्रदान किया। यह आज भी भारत की विदेश नीति के नैतिक और व्यावहारिक आधार के रूप में अत्यंत प्रासंगिक है, जो वैश्विक दक्षिण के राष्ट्रों के बीच अपनी सामूहिक आवाज और उनके स्वाभिमान का प्रतीक बना हुआ है।

215. (B) केवल 2 और 3
भारत के लिए सीमा पार आतंकवाद एक स्थाई और गंभीर सुरक्षा खतरा बना हुआ है, जो इसकी आंतरिक शांति और क्षेत्रीय स्थिरता को निरंतर चुनौती देता है। इसके अतिरिक्त, दक्षिण एशिया और हिंद महासागर क्षेत्र में चीन का बढ़ता रणनीतिक और आर्थिक प्रभाव भारत के लिए एक नई और महत्वपूर्ण सुरक्षा चिंता बनकर उभरा है। हालांकि, भारत का इतिहास सैन्य गठबंधनों से दूरी बनाए रखने का रहा है, इसलिए यह कहना गलत है कि इसके प्रमुख सुरक्षा समझौते पश्चिमी शक्तियों के साथ रहे हैं। भारत ने सदैव अपनी रणनीतिक

NODIA

की दिशा में एक महत्वपूर्ण और दूरदर्शी दस्तावेज सिद्ध हुई है, जिसने अंतरराष्ट्रीय विकास वार्ताओं के एजेंडे को नया विस्तार प्रदान किया। यह संवाद वैश्विक आर्थिक असमानता को दूर करने और निर्धन राष्ट्रों को अंतरराष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली में सक्रिय और समान भागीदार बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया की महत्ता को रेखांकित करता है।

205. (D) A गलत है लेकिन R सही है।
विश्व व्यापार संगठन में तकनीकी रूप से प्रत्येक सदस्य के पास एक वोट होता है, लेकिन व्यवहार में मतदान की प्रक्रिया का उपयोग बहुत कम किया जाता है। इसके स्थान पर, सभी महत्वपूर्ण निर्णय आम सहमति के माध्यम से लिए जाते हैं, जहाँ पर्दे के पीछे शक्तिशाली व्यापारिक राष्ट्रों का अत्यधिक प्रभाव होता है। अक्सर विकसित देश अपनी आर्थिक शक्ति के बल पर वार्ताओं के एजेंडे को नियंत्रित करते हैं। यह स्थिति विकासशील राष्ट्रों के लिए चुनौतीपूर्ण होती है क्योंकि वे अपनी मांगों को प्रभावी ढंग से मनवाने के लिए पर्याप्त दबाव नहीं बना पाते हैं। यह बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली में मौजूद शक्ति के असंतुलन और लोकतांत्रिक समावेशिता की कमी को स्पष्ट रूप से उजागर करता है। यद्यपि आम सहमति का सिद्धांत निष्पक्षता का आभास देता है, परंतु वास्तविक निर्णय लेने की प्रक्रिया में आर्थिक रूप से सुदृढ़ राष्ट्रों का निर्णायक प्रभाव अंतरराष्ट्रीय व्यापार नियमों को उनके हितों के अनुकूल बनाने में सफल रहता है, जो वैश्विक आर्थिक न्याय के लिए एक निरंतर चुनौती है।

206. (C) जी-20 (G-20)
सार्क, आसियान और ओएएस अपनी संरचना और सदस्यता में विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों तक सीमित हैं, जो उन्हें क्षेत्रीय संगठन बनाता है। इसके विपरीत, जी-20 की सदस्यता में दुनिया भर की प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं, जो किसी एक क्षेत्र से बंधी हुई नहीं हैं। इसमें एशिया, यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका के महत्वपूर्ण राष्ट्र शामिल हैं। यह एक वैश्विक मंच है जिसका मुख्य उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता और आर्थिक सहयोग पर चर्चा करना है। इसकी सदस्यता इसके भौगोलिक स्थान के बजाय इसकी आर्थिक शक्ति और वैश्विक प्रभाव पर आधारित होती है। यह विविधता जी-20 को वैश्विक आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करने और प्रभावी नीतिगत समन्वय स्थापित करने के लिए एक अत्यंत संतुलित और शक्तिशाली अंतरराष्ट्रीय निकाय बनाती है। वर्तमान वैश्विक आर्थिक शासन में जी-20 की भूमिका अपरिहार्य हो गई है, क्योंकि यह विकसित और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाकर वैश्विक चुनौतियों का सामूहिक समाधान खोजने के लिए एक प्रभावी और समावेशी मंच प्रदान करता है।

207. (C) सार्क (SAARC)
"साफ़्टा" दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के सदस्य देशों के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक समझौता है। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य दक्षिण एशिया में व्यापारिक बाधाओं को दूर करना और सदस्य राष्ट्रों के बीच वस्तुओं के मुक्त प्रवाह को सुगम बनाना था। यह समझौता क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम माना गया था। यद्यपि राजनीतिक तनावों के कारण इसकी पूर्ण क्षमता का उपयोग नहीं हो सका है, लेकिन यह सार्क के भीतर आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए की गई सबसे महत्वपूर्ण कानूनी और नीतिगत पहल बनी हुई है। दक्षिण एशियाई क्षेत्र के आर्थिक उत्थान और सदस्य देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए साफ़्टा का प्रभावी कार्यान्वयन अनिवार्य है। यह क्षेत्रीय एकीकरण और साझा समृद्धि के प्रति सार्क की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आर्थिक सहयोग के माध्यम से क्षेत्रीय शांति और विकास सुनिश्चित करने की दिशा में यह समझौता एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान करने की क्षमता रखता है, जो दक्षिण एशिया के भविष्य के लिए निर्णायक है।

208. (C) सार्वजनिक टकराव और कानूनी दृष्टिकोण।
'आसियान शैली' की कूटनीति विवादों को निजी और अनौपचारिक वार्ताओं के माध्यम से सुलझाने पर बल देती है। यह सदस्य देशों के बीच सार्वजनिक रूप से एक-दूसरे की आलोचना करने या विवादों को अदालतों में ले जाने से बचती है। इसके स्थान पर, परामर्श और आम सहमति को प्राथमिकता दी जाती है ताकि क्षेत्रीय एकता और "चेहरा बचाने" की संस्कृति बनी रहे। यह दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि मतभेदों के बावजूद सहयोग का वातावरण प्रभावित न हो। यह अनूठी पद्धति आसियान को एक स्थिर और एकजुट क्षेत्रीय समूह बनाए रखने में सहायक रही है। यह एशियाई कूटनीति का एक बहुत ही प्रभावशाली मॉडल माना जाता है जो संप्रभुता के सम्मान और परस्पर विश्वास पर आधारित है। यह क्षेत्रीय स्थिरता और सामूहिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुपक्षीय संवाद की महत्ता को रेखांकित करता है। यह विविधतापूर्ण प्रणालियों के बावजूद राष्ट्रों को एक साथ लाने और उनमें सहयोग की भावना विकसित करने में अत्यंत सहायक सिद्ध हुई है।

209. (A) जी-7 अकेला अब वैश्विक अर्थव्यवस्था का प्रबंधन नहीं कर सकता था।
2008 के वैश्विक संकट ने यह सिद्ध कर दिया कि अब केवल धनी देशों का समूह, यानी जी-7, दुनिया की जटिल आर्थिक समस्याओं को हल करने में सक्षम नहीं है। उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं जैसे भारत और चीन के सहयोग के बिना वैश्विक वित्तीय स्थिरता प्राप्त करना असंभव था। इसी अहसास ने जी-20 को राष्ट्राध्यक्षों के स्तर पर एक अनिवार्य मंच बना दिया। यह बदलाव वैश्विक शक्ति संतुलन में आए परिवर्तन को दर्शाता है, जहाँ विकासशील राष्ट्रों की भूमिका अब वैश्विक शासन में अनिवार्य और अत्यंत निर्णायक हो गई है। जी-20 की समावेशी प्रकृति इसे वैश्विक वित्तीय चुनौतियों का सामना करने के लिए अधिक वैध और प्रभावी मंच बनाती है। यह वर्तमान वैश्विक आर्थिक शासन का एक अत्यंत प्रभावी माध्यम है जो विकसित और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाकर सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संवाद का वातावरण तैयार करता है। यह वैश्विक सहयोग के इतिहास में एक निर्णायक और ऐतिहासिक मोड़ सिद्ध हुआ है।

Click Here to Buy book on Amazon

वैश्विक उत्तरदायित्वों को पूरा करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है।

231. (C) सतत विकास लक्ष्य (SDGs)।
संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य शांति और विकास के बीच के अटूट संबंध को सबसे व्यापक रूप से प्रदर्शित करते हैं। ये 17 लक्ष्य गरीबी उन्मूलन, सामाजिक न्याय और पर्यावरणीय स्थिरता के साथ-साथ शांतिपूर्ण और समावेशी समाज के निर्माण पर भी बल देते हैं। संगठन का मानना है कि वास्तविक शांति तभी संभव है जब लोगों के पास विकास के समान अवसर हों और उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा हो। एसडीजी 2030 तक एक ऐसी दुनिया बनाने का वैश्विक संकल्प है जहाँ प्रगति और शांति एक-दूसरे के पूरक के रूप में साथ चल सकें। यह ढांचा अंतरराष्ट्रीय सहयोग के लिए एक आधुनिक और व्यापक मार्गदर्शिका है जो वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए एक एकीकृत और प्रभावी रणनीति प्रस्तुत करता है। यह अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के साथ-साथ मानवीय कल्याण और पर्यावरणीय स्थिरता के बीच के गहरे संबंधों को स्पष्ट रूप से उजागर करता है। यह 21वीं सदी के वैश्विक एजेंडे को दिशा प्रदान करने वाली एक अनिवार्य और दूरदर्शी नीतिगत रूपरेखा है जो सभी के लिए न्यायसंगत भविष्य सुनिश्चित करने हेतु संकल्पबद्ध है।

232. (C) किसी भी संशोधन के लिए P5 की सहमति की आवश्यकता।
संयुक्त राष्ट्र चार्टर में संशोधन करना दुनिया की सबसे कठिन कानूनी प्रक्रियाओं में से एक है। इसकी मुख्य बाधा यह है कि किसी भी बदलाव को सुरक्षा परिषद के पांचों स्थाई सदस्यों द्वारा अनिवार्य रूप से अनुमोदित किया जाना चाहिए। यदि इनमें से एक भी देश अपनी वीटो शक्ति का उपयोग करता है, तो संशोधन प्रक्रिया वहीं समाप्त हो जाती है। यह शर्त सुरक्षा परिषद की संरचना में सुधार या स्थाई सदस्यों के विशेषाधिकारों को कम करने के किसी भी प्रयास को लगभग असंभव बना देती है। इसके कारण चार्टर में बदलाव की प्रक्रिया अत्यंत धीमी और चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। यह संगठन के भीतर संवैधानिक सुधार और वर्तमान वैश्विक वास्तविकताओं के अनुरूप इसके विकास की राह में एक स्थाई और ऐतिहासिक अवरोध है। सुरक्षा परिषद को अधिक प्रतिनिधि और प्रभावी बनाने के लिए इस प्रक्रिया का लचीला होना अनिवार्य है, परंतु वीटो की शक्ति सुधार के किसी भी साहसिक प्रस्ताव को विफल करने की क्षमता रखती है। यह अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा प्रबंधन के ढांचे में लोकतांत्रिक सुधारों के प्रति एक स्थाई और जटिल चुनौती है।

233. (C) मध्यस्थ भूमिका (Mediatory role)
"मध्यम शक्ति" के रूप में भारत ने अक्सर अंतरराष्ट्रीय विवादों में एक संतुलित और निष्पक्ष मध्यस्थ की भूमिका निभाई है। ऐसी शक्तियां महाशक्तियों के संघर्ष में पक्ष लेने के बजाय शांतिपूर्ण समाधान और संवाद को बढ़ावा देने का प्रयास करती हैं। भारत ने कोरियाई युद्ध और स्वेज संकट जैसे मामलों में अपनी इस क्षमता का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है। यह भूमिका किसी राष्ट्र के नैतिक प्रभाव और उसके राजनयिक कौशल पर निर्भर करती है। मध्यम शक्ति कूटनीति का उद्देश्य वैश्विक व्यवस्था में स्थिरता बनाए रखना और छोटे एवं बड़े राष्ट्रों के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करना होता है। यह अंतरराष्ट्रीय संबंधों में संवाद और सहयोग की महत्ता को रेखांकित करने वाली एक महत्वपूर्ण और प्रभावी कूटनीतिक रणनीति है। भारत की यह सकारात्मक और रचनात्मक भूमिका क्षेत्रीय और वैश्विक तनावों को कम करने और मानवीय संकटों को सुलझाने में महत्वपूर्ण सिद्ध हुई है। यह भारत की स्वतंत्र और जिम्मेदार वैश्विक भूमिका का आधार है, जो उसे अंतरराष्ट्रीय मंच पर एक विश्वसनीय और न्यायप्रिय शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित करता है।

234. (D) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।
गुजराल सिद्धांत का मूल मंत्र यह है कि भारत को अपने छोटे पड़ोसियों के साथ संबंधों में पारस्परिकता नहीं मांगनी चाहिए, बल्कि एकतरफा उदारता दिखानी चाहिए। यह सिद्धांत इस धारणा पर आधारित था कि दक्षिण एशिया में एक बड़ा भाई होने के नाते भारत को विश्वास निर्माण के लिए पहला कदम उठाना चाहिए। यह नीति मुख्य रूप से नेपाल, भूटान, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे निकटवर्ती छोटे राष्ट्रों के लिए ही बनाई गई थी। अतः, यह कहना गलत है कि इसमें सख्त पारस्परिकता का पालन किया गया था, क्योंकि इसकी पूरी अवधारणा ही उदारता पर टिकी थी। यह दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग की संभावनाओं को सुदृढ़ करने और अविश्वास को कम करने में एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक भूमिका निभाने वाला रणनीतिक बदलाव था। गुजराल सिद्धांत आज भी भारत की क्षेत्रीय कूटनीति में विश्वास निर्माण और पड़ोसी राष्ट्रों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंधों के प्रति उसकी निरंतर प्रतिबद्धता का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसने भारत की एक सहयोगी साझेदार के रूप में छवि को सुदृढ़ किया और क्षेत्रीय शांति के लिए एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया।

235. (C) भारतीय विदेश नीति
"रणनीतिक स्वायत्तता" आधुनिक भारतीय विदेश नीति की एक प्रमुख विशेषता है, जो गुटनिरपेक्षता के पुराने सिद्धांतों का ही एक नया और व्यावहारिक स्वरूप है। इसका अर्थ है कि भारत किसी भी शक्ति गुट के साथ स्थाई गठबंधन किए बिना अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर स्वतंत्र निर्णय लेता है। यह भारत को अमेरिका, रूस और चीन जैसी विभिन्न शक्तियों के साथ साथ-साथ जुड़ने की सुविधा प्रदान करता है। यह दृष्टिकोण एक बहुध्रुवीय विश्व में भारत की स्वतंत्र पहचान को मजबूत करता है और उसे अपनी सुरक्षा और आर्थिक हितों को सर्वोत्तम रूप से सुरक्षित रखने में सहायता देता है। यह राष्ट्रीय संप्रभुता और वैश्विक शांति के प्रति भारत की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करता है। यह नीति की गतिशीलता और बदलती वैश्विक परिस्थितियों के अनुरूप भारत की कूटनीतिक स्वाधीनता और उसके वैश्विक लक्ष्यों की प्राप्ति का एक अनिवार्य और प्रभावी आधार है। रणनीतिक स्वायत्तता आज भारत को अंतरराष्ट्रीय मंच पर एक स्वतंत्र, विश्वसनीय और प्रभावशाली खिलाड़ी के रूप में अपनी भूमिका निभाने की पूरी स्वाधीनता और शक्ति प्रदान करती है।

NODIA

स्वायत्तता को प्राथमिकता दी है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय शांति के प्रति भारत की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता और उसके नैतिक आदर्शों को प्रतिबिंबित करता है। भारत की सुरक्षा नीति मुख्य रूप से उन खतरों पर केंद्रित है जो सीधे तौर पर उसकी क्षेत्रीय अखंडता और आंतरिक शांति को प्रभावित करते हैं। हिंद महासागर क्षेत्र की सुरक्षा भारत के राष्ट्रीय हितों के लिए सर्वोपरि है, जो कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर निरंतर ध्यान केंद्रित करने की मांग करती है।

216. (A) मध्यस्थ भूमिका (Mediatory role)
कोरियाई युद्ध के दौरान भारत ने एक निष्पक्ष और शांतिप्रिय राष्ट्र के रूप में अपनी छवि स्थापित की थी। भारत ने संघर्षरत पक्षों के बीच संवाद का सेतु बनकर युद्धविराम और मानवीय संकटों को सुलझाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस मध्यस्थता ने यह सिद्ध किया कि कोई देश बिना किसी गुट में शामिल हुए भी वैश्विक शांति के लिए प्रभावी कार्य कर सकता है। यह भूमिका भारतीय विदेश नीति के उस मूल मंत्र का प्रमाण थी जो युद्ध के स्थान पर सदैव कूटनीतिक और शांतिपूर्ण समाधानों की वकालत करती रही है। भारत की मध्यस्थ भूमिका सदैव इस विश्वास पर टिकी रही है कि संघर्षों का स्थाई समाधान केवल बातचीत और आपसी समझ के माध्यम से ही संभव है। यह अंतरराष्ट्रीय संबंधों में संवाद और सहयोग की महत्ता को रेखांकित करने वाली एक महत्वपूर्ण और प्रभावी कूटनीतिक रणनीति है। भारत की यह सकारात्मक और रचनात्मक भूमिका क्षेत्रीय और वैश्विक तनावों को कम करने में महत्वपूर्ण सिद्ध हुई है, जो अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में भारत के बढ़ते प्रभाव का प्रतीक है।

217. (B) दक्षिण-पूर्व और पूर्व एशिया के साथ जुड़ाव के लिए अधिक सक्रिय और कार्रवाई-उन्मुख दृष्टिकोण।
'लुक ईस्ट' से 'एक्ट ईस्ट' नीति की ओर बदलाव भारत की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं और क्षेत्र में अधिक ठोस भूमिका निभाने की इच्छा को दर्शाता है। जहाँ पुरानी नीति मुख्य रूप से आर्थिक संबंधों पर केंद्रित थी, वहीं नई नीति सुरक्षा, कनेक्टिविटी और सांस्कृतिक आदान-प्रदान पर अधिक बल देती है। इसका उद्देश्य दक्षिण-पूर्व और पूर्व एशियाई देशों के साथ एक गहरी और व्यापक रणनीतिक साझेदारी विकसित करना है। यह बदलाव भारत की विदेश नीति में एक अधिक सक्रिय और परिणाम-उन्मुख कूटनीति के युग की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। यह नीति की गतिशीलता और बदलती वैश्विक परिस्थितियों के अनुरूप भारत की कूटनीतिक और आर्थिक दिशा को नया विस्तार प्रदान करने का एक सफल प्रयास है। इसने भारत को एशिया-प्रशांत क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण आर्थिक और रणनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित करने में मदद की है। यह क्षेत्रीय एकीकरण और सुरक्षा सहयोग के प्रति भारत की सक्रियता को दर्शाता है, जो वर्तमान बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में अत्यंत आवश्यक और महत्वपूर्ण है।

218. (B) पंचशील
पंचशील शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के पांच सिद्धांतों का एक समूह है, जो भारत और चीन के बीच 1954 में हुए समझौते से लोकप्रिय हुआ। ये सिद्धांत राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और मैत्रीपूर्ण संबंधों के लिए एक नैतिक रूपरेखा प्रदान करते हैं। इनमें एक-दूसरे की संप्रभुता का सम्मान और आंतरिक मामलों में अहस्तक्षेप जैसे महत्वपूर्ण स्तंभ शामिल हैं। यद्यपि ये सिद्धांत प्राचीन भारतीय दर्शन से प्रेरित हैं, परंतु आधुनिक अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में भी इनकी प्रासंगिकता बनी हुई है। ये सिद्धांत भारत की शांतिप्रिय विदेश नीति के शाश्वत आदर्श माने जाते हैं। पंचशील का मूल उद्देश्य राष्ट्रों के बीच विश्वास का वातावरण बनाना और युद्ध की संभावनाओं को कम करना था। ये सिद्धांत अंतरराष्ट्रीय संबंधों में संप्रभु समानता और न्यायसंगत व्यवस्था की वकालत करते हैं। यद्यपि बाद के वर्षों में इन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ा, फिर भी ये भारतीय कूटनीति के नैतिक आधार बने हुए हैं। यह अंतरराष्ट्रीय संबंधों में शांतिपूर्ण संवाद और परस्पर सम्मान सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक ऐतिहासिक दस्तावेज है।

219. (B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
विदेश नीति उन लक्ष्यों और सिद्धांतों का एक व्यापक समूह है जो किसी राष्ट्र के अंतरराष्ट्रीय संबंधों और प्राथमिकताओं को निर्धारित करते हैं। इसके विपरीत, कूटनीति वह माध्यम और प्रक्रिया है जिसके द्वारा उन विदेश नीति के लक्ष्यों को धरातल पर प्राप्त करने के लिए बातचीत और संवाद किया जाता है। अतः, विदेश नीति 'क्या प्राप्त करना है' यह तय करती है, जबकि कूटनीति 'कैसे प्राप्त करना है' यह सुनिश्चित करती है। इन दोनों का आपसी संबंध अत्यंत गहरा है, क्योंकि प्रभावी कूटनीति के बिना कोई भी विदेश नीति सफल नहीं हो सकती है। कूटनीति वह अनिवार्य साधन है जो बिना युद्ध के राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने का प्रयास करता है। एक सफल कूटनीति राष्ट्र की प्रतिष्ठा और उसके वैश्विक प्रभाव को सुदृढ़ करती है, जिससे शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व और न्यायसंगत अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का निर्माण संभव होता है। यह अंतरराष्ट्रीय राजनीति के जटिल अंतर्संबंधों को प्रबंधित करने और राष्ट्रहितों के साथ वैश्विक लक्ष्यों के बीच तालमेल बनाने का एक अनिवार्य और प्रभावी माध्यम है, जो राष्ट्रीय प्रगति के लिए निर्णायक है।

220. (B) राजनीतिक शक्ति और आर्थिक संपदा आंतरिक रूप से जुड़े हुए हैं और एक-दूसरे को सुदृढ़ करते हैं।
अंतरराष्ट्रीय संबंधों का राजनीतिक-आर्थिक दृष्टिकोण यह मानता है कि राजनीति और अर्थशास्त्र को एक-दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। राज्य की राजनीतिक शक्ति अक्सर उसकी आर्थिक क्षमता पर निर्भर करती है, और आर्थिक नियम अक्सर राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं। यह विचारधारा वैश्विक व्यापार, वित्तीय प्रवाह और संसाधनों के वितरण को शक्ति संबंधों के आईने में देखती है। यह समझने में मदद करता है कि कैसे राष्ट्र अपनी आर्थिक नीतियों का उपयोग वैश्विक मंच पर अपना राजनीतिक प्रभाव और प्रभुत्व बढ़ाने के लिए करते हैं। यह अंतरराष्ट्रीय संबंधों के वास्तविक आधारों का तार्किक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। यह राष्ट्रों की संप्रभुता और वैश्विक आर्थिक शासन के बीच के जटिल अंतर्संबंधों को स्पष्ट करने वाला एक महत्वपूर्ण सैद्धांतिक दृष्टिकोण है। यह बदलते हुए विश्व की जटिलताओं का विश्लेषण करने का एक

Downloaded from www.pdf.tube

199. (B) निष्पक्षता (Impartiality)
निष्पक्षता संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना का एक मौलिक सिद्धांत है, जिसका अर्थ है कि शांति सैनिकों को किसी भी स्थिति में संघर्ष के किसी एक पक्ष का समर्थन नहीं करना चाहिए। उन्हें अपनी जिम्मेदारी निभाते समय निष्पक्ष और तटस्थ बने रहना अनिवार्य है ताकि संघर्षरत पक्षों का संगठन में विश्वास बना रहे। यदि शांति सैनिक पक्षपाती दिखाई देते हैं, तो शांति प्रक्रिया की विश्वसनीयता समाप्त हो सकती है और अभियान विफल हो सकता है। यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि संयुक्त राष्ट्र एक ईमानदार मध्यस्थ के रूप में शांति समझौतों को सफलतापूर्वक लागू कर सके। यह संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में स्थिरता बहाल करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयासों को नैतिक और कूटनीतिक मजबूती प्रदान करता है। शांति अभियानों की सफलता के लिए निष्पक्षता के साथ-साथ मेजबान राष्ट्र की सहमति और केवल आत्मरक्षा में बल प्रयोग की नीति का पालन करना भी अनिवार्य है। यह वैश्विक शांति स्थापना के मानवीय मिशन का एक आधारभूत और पवित्र स्तंभ है।

200. (A) नदी जल बंटवारा और अवैध प्रवास।
भारत और बांग्लादेश के संबंधों में नदी जल का बंटवारा, विशेष रूप से तीस्ता नदी का मुद्दा, एक लंबे समय से चला आ रहा विवाद रहा है। इसके अतिरिक्त, अवैध प्रवास और सीमाओं पर होने वाली घुसपैठ ने भी दोनों देशों के बीच समय-समय पर सुरक्षा और राजनीतिक तनाव उत्पन्न किया है। साझा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों के बावजूद, ये मुद्दे द्विपक्षीय वार्ताओं में निरंतर प्राथमिकता बने रहते हैं। इन चुनौतियों का समाधान करना दोनों देशों के लिए क्षेत्रीय स्थिरता और आर्थिक सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए अत्यंत अनिवार्य और महत्वपूर्ण कार्य है। भारत की "पड़ोसी पहले" नीति के तहत इन विवादों को शांतिपूर्ण संवाद और आपसी समझ के माध्यम से हल करने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। द्विपक्षीय संबंधों में सुधार के लिए जल संसाधन प्रबंधन और सीमा सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दों पर प्रभावी सहयोग अनिवार्य है, जो पूरे दक्षिण एशियाई क्षेत्र की शांति और समृद्धि के लिए निर्णायक भूमिका निभा सकता है।

201. (C) इसके निकटवर्ती छोटे पड़ोसी देश
गुजराल सिद्धांत भारत की एक उदार और दूरदर्शी कूटनीतिक पहल थी जो विशेष रूप से दक्षिण एशिया के छोटे पड़ोसी राष्ट्रों के साथ संबंधों को सुधारने के लिए बनाई गई थी। इसका मूल विचार यह था कि भारत को अपने पड़ोसियों के प्रति उदारता दिखानी चाहिए और उनसे किसी तत्काल लाभ की अपेक्षा किए बिना सहयोग करना चाहिए। यह नीति विश्वास की कमी को दूर करने और क्षेत्रीय शांति का वातावरण तैयार करने में सफल रही। इसने छोटे राष्ट्रों को यह आश्वासन दिया कि भारत उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। यह दृष्टिकोण भारत के दक्षिण एशियाई क्षेत्र में "बड़े भाई" की छवि को बदलकर एक विश्वसनीय और सहयोगी साझेदार के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक बदलाव था। गुजराल सिद्धांत आज भी भारत की क्षेत्रीय कूटनीति में विश्वास निर्माण और पड़ोसी राष्ट्रों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंधों के प्रति उसकी निरंतर प्रतिबद्धता का एक उत्कृष्ट और प्रभावशाली उदाहरण माना जाता है।

202. (B) क्वामे न्क्रूमा
घाना के महान नेता क्वामे न्क्रूमा ने नव-उपनिवेशवाद की अवधारणा को वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत किया और इसे साम्राज्यवाद का अंतिम चरण बताया। उन्होंने तर्क दिया कि यद्यपि कई अफ्रीकी राष्ट्र स्वतंत्र हो गए हैं, लेकिन उनकी आर्थिक प्रणालियां अभी भी बाहरी शक्तियों द्वारा नियंत्रित की जा रही हैं। न्क्रूमा ने आगाह किया था कि यह आर्थिक निर्भरता राष्ट्रों की वास्तविक संप्रभुता को खोखला कर देती है। उनके विचारों ने विकासशील देशों को अपनी आर्थिक नीतियों पर फिर से विचार करने और सामूहिक आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया था। यह अवधारणा आधुनिक समय में शोषण के सूक्ष्म रूपों को समझने और राष्ट्रों की संप्रभुता के प्रति जागरूक रहने के लिए अनिवार्य है। न्क्रूमा का यह सैद्धांतिक योगदान अंतरराष्ट्रीय संबंधों में आर्थिक शक्ति के अप्रत्यक्ष प्रभुत्व को उजागर करने वाला एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने वैश्विक दक्षिण के राष्ट्रों के बीच अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए एक नई राजनीतिक और वैचारिक चेतना जागृत की।

203. (C) निर्भरता सिद्धांत
राउल प्रेबिश और हंस सिंगर ने व्यापार की शर्तों में गिरावट की ऐतिहासिक प्रवृत्ति का विश्लेषण किया, जो निर्भरता सिद्धांत की आर्थिक आधारशिला बनी। उनका तर्क था कि प्राथमिक वस्तुओं के निर्यातकों (परिधि) को निर्मित वस्तुओं के निर्यातकों (केंद्र) की तुलना में निरंतर आर्थिक नुकसान होता है। यह संरचनात्मक असमानता विकासशील देशों को विकसित देशों पर निर्भर बनाए रखती है। इस शोध ने यह सिद्ध किया कि केवल मुक्त व्यापार विकास की गारंटी नहीं देता, बल्कि इसके लिए वैश्विक आर्थिक ढांचे में मौलिक बदलाव की आवश्यकता है, जो विकासशील देशों के अनुकूल हो। यह अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंधों के भीतर मौजूद शोषणकारी प्रवृत्तियों का गहराई से विश्लेषण करने वाला एक महत्वपूर्ण सैद्धांतिक ढांचा प्रस्तुत करता है। प्रेबिश-सिंगर परिकल्पना ने वैश्विक आर्थिक शासन में समानता और न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में विकासशील राष्ट्रों की साझा आकांक्षाओं और उनके संगठित कूटनीतिक प्रयासों को एक मजबूत वैज्ञानिक और आर्थिक आधार प्रदान करने का महत्वपूर्ण कार्य किया।

204. (A) उत्तर-दक्षिण संवाद।
ब्रांट आयोग की रिपोर्टों ने दुनिया का ध्यान विकसित और विकासशील देशों के बीच मौजूद गहरी आर्थिक खाई की ओर आकर्षित किया। इन रिपोर्टों ने तर्क दिया कि उत्तरी राष्ट्रों की समृद्धि और दक्षिणी राष्ट्रों का विकास एक-दूसरे पर निर्भर हैं। इसने वैश्विक गरीबी को दूर करने के लिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार और वित्त प्रणालियों में सुधार का एक व्यापक कार्यक्रम प्रस्तावित किया। इन विचारों ने उत्तर-दक्षिण संवाद को एक नई ऊर्जा प्रदान की और यह संदेश दिया कि मानवता की उत्तरजीविता के लिए राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत सहयोग अपरिहार्य है। ब्रांट रिपोर्ट वैश्विक न्याय और सामूहिक समृद्धि

NODIA

सार्क के विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय एकीकरण की दिशा में एक अनिवार्य स्तंभ बना हुआ है। यह क्षेत्रीय संगठनों की विशिष्ट भौगोलिक और रणनीतिक सीमाओं को स्पष्ट करता है।

226. (D) उपरोक्त सभी
चक्रीय अध्यक्षता की व्यवस्था इन सभी संगठनों में नेतृत्व के अवसर को समान रूप से साझा करने के लिए अपनाई जाती है। सुरक्षा परिषद में प्रत्येक सदस्य एक महीने के लिए अध्यक्षता करता है। जी-20 में यह अध्यक्षता वार्षिक होती है और एक सदस्य से दूसरे सदस्य के पास जाती है। ओपेक में भी नेतृत्व का पद सदस्य देशों के बीच बदलता रहता है। यह प्रणाली संगठन के भीतर लोकतांत्रिक भागीदारी सुनिश्चित करती है और किसी एक राष्ट्र के स्थाई प्रभुत्व को रोकती है। यह सभी सदस्यों को संगठन के एजेंडे को प्रभावित करने का अवसर प्रदान करती है। यह अंतरराष्ट्रीय शासन में समानता और समावेशिता के सिद्धांतों को सुदृढ़ करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। चक्रीय नेतृत्व संरचना संगठनों के भीतर परस्पर विश्वास को बढ़ावा देती है और निर्णय लेने की प्रक्रिया में विभिन्न क्षेत्रीय एवं आर्थिक दृष्टिकोणों को उचित स्थान प्रदान करती है। यह वैश्विक और क्षेत्रीय कूटनीति में लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रभावी क्रियान्वयन का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जो संस्थानों की स्थिरता और स्वीकार्यता सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य है।

227. (A) 'A' और 'R' दोनों सही हैं और 'R', 'A' की सही व्याख्या है।
सार्क की तुलना में आसियान की सफलता का मुख्य कारण यह है कि आसियान देशों ने अपने द्विपक्षीय विवादों को क्षेत्रीय सहयोग के मार्ग में बाधा नहीं बनने दिया। इसके विपरीत, सार्क के दो प्रमुख देशों, भारत और पाकिस्तान, के बीच के निरंतर राजनीतिक संघर्ष और अविश्वास ने संगठन की प्रगति को लगभग रोक दिया है। जब भी द्विपक्षीय तनाव बढ़ता है, तो सार्क की बैठकें और शिखर सम्मेलन प्रभावित होते हैं। इसके कारण आर्थिक एकीकरण और साझा विकास की योजनाएं प्रभावी ढंग से लागू नहीं हो पाती हैं। राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी संगठन की विफलता का मुख्य कारण बनी हुई है। दक्षिण एशियाई क्षेत्र के समग्र विकास और एकीकरण के लिए इन द्विपक्षीय मतभेदों को दूर करना और परस्पर विश्वास बहाल करना अनिवार्य है। यह सार्क की भविष्य की प्रासंगिकता और क्षेत्रीय शांति के लिए एक निर्णायक कारक है। आसियान की "आम सहमति" वाली कार्यसंस्कृति सार्क के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण हो सकती है ताकि दक्षिण एशिया अपनी विशाल क्षमता का पूर्ण उपयोग कर सके और साझा समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ सके।

228. (A) अहस्तक्षेप (Non-intervention)।
अमेरिकी राज्यों के संगठन का संस्थापक चार्टर लोकतंत्र की रक्षा के साथ-साथ सदस्य राष्ट्रों की संप्रभुता और अहस्तक्षेप के सिद्धांत पर विशेष बल देता है। यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि कोई भी देश दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करे, जो क्षेत्र की राजनीतिक स्थिरता के लिए आवश्यक है। ओएएस का उद्देश्य पश्चिमी गोलार्ध में विवादों का शांतिपूर्ण समाधान खोजना और आपसी सहयोग बढ़ाना है। अहस्तक्षेप का यह मूल्य लैटिन अमेरिकी देशों के लिए ऐतिहासिक रूप से अपनी स्वतंत्रता और स्वायत्तता को सुरक्षित रखने का एक महत्वपूर्ण माध्यम रहा है। यह क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण संस्थागत आधार प्रदान करता है। ओएएस की महत्ता इसके द्वारा स्थापित क्षेत्रीय सहयोग के व्यापक और समावेशी ढांचे में निहित है, जो पश्चिमी गोलार्ध के राष्ट्रों के बीच कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करने और सामूहिक चुनौतियों का सामना करने के लिए एक स्थाई और सुदृढ़ आधार प्रदान करता है। यह अंतरराष्ट्रीय संबंधों में संप्रभु समानता और परस्पर सम्मान सुनिश्चित करने की दिशा में एक अनिवार्य सिद्धांत है।

229. (B) अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना।
संयुक्त राष्ट्र की स्थापना का सर्वोपरि लक्ष्य दुनिया में शांति स्थापित करना और युद्धों को रोकना है। चार्टर के अनुसार, संगठन का मुख्य कार्य राष्ट्रों के बीच के विवादों को सुलझाना और आक्रामकता के विरुद्ध सामूहिक कार्रवाई करना है। यह सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा पर आधारित है, जहाँ सभी सदस्य राष्ट्र शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी साझा करते हैं। हालांकि संगठन के अन्य कई उद्देश्य भी हैं, जैसे मानवाधिकार और विकास, परंतु सुरक्षा और शांति ही इसकी आधारशिला और सबसे महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व माना जाता है, जो इसकी पूरी संरचना को संचालित करता है। यह वैश्विक शासन की आधारशिला और अंतरराष्ट्रीय सहयोग का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना मानवता के बेहतर और सुरक्षित भविष्य के लिए एक वैश्विक संकल्प का प्रतीक थी। यह संगठन आज भी अंतरराष्ट्रीय राजनीति और सुरक्षा प्रबंधन में एक निर्णायक और अपरिहार्य भूमिका निभाता है। शांति और सुरक्षा बनाए रखने का यह प्राथमिक उत्तरदायित्व संगठन की वैश्विक प्रासंगिकता और उसकी प्रभावशीलता को सुदृढ़ करने के लिए एक अनिवार्य आधार प्रदान करता है।

230. (B) सुरक्षा परिषद वीटो के कारण गतिरोध में हो।
"शांति के लिए एकता" प्रस्ताव एक विशेष कूटनीतिक उपकरण है जो तब सक्रिय होता है जब सुरक्षा परिषद के स्थाई सदस्य अपने वीटो का उपयोग करके किसी महत्वपूर्ण निर्णय को रोक देते हैं। ऐसी स्थिति में, महासभा आपातकालीन सत्र बुलाकर अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बहाल करने के लिए उचित सिफारिशें कर सकती है। यह प्रस्ताव सुनिश्चित करता है कि महाशक्तियों के आपसी मतभेदों के कारण संयुक्त राष्ट्र पूरी तरह से निष्क्रिय न हो जाए। यह महासभा को संकट के समय में एक अधिक प्रभावी और निर्णायक भूमिका निभाने का अवसर और कानूनी आधार प्रदान करता है। यह अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में महासभा की भूमिका को सुदृढ़ करता है और महाशक्तियों के वीटो के कारण होने वाले गतिरोध को दूर करने का एक प्रभावी मार्ग प्रदान करता है। यह वैश्विक सुरक्षा और शांति स्थापना की दिशा में संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों की अनुकूलन क्षमता और उसकी प्रशासनिक सूझबूझ का एक ऐतिहासिक प्रमाण है। यह संगठन की लोकतांत्रिक वैधता को सुदृढ़ करने और सामूहिक

Click Here to Buy book on Amazon

प्रभावी माध्यम है, जो यह स्पष्ट करता है कि वैश्विक शासन में आर्थिक और राजनीतिक हित कैसे आपस में गुंथे हुए हैं और राष्ट्रहित की प्राप्ति हेतु इनका समन्वय अनिवार्य है।

221. (A) एक अधिक न्यायसंगत वैश्विक आर्थिक प्रणाली।
उत्तर-दक्षिण संवाद में दक्षिण के देशों की मुख्य मांग यह थी कि मौजूदा अंतरराष्ट्रीय आर्थिक ढांचा उनके प्रति भेदभावपूर्ण है और इसमें सुधार की आवश्यकता है। वे कच्चे माल के लिए उचित मूल्य, बेहतर व्यापारिक पहुंच और विकसित देशों से अधिक तकनीकी एवं वित्तीय सहायता चाहते थे। उनका तर्क था कि बिना आर्थिक न्याय के उनकी राजनीतिक स्वतंत्रता अधूरी है। यह मांग केवल सहायता प्राप्त करने के लिए नहीं थी, बल्कि वैश्विक आर्थिक निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनी समान भागीदारी और संप्रभुता सुनिश्चित करने के लिए एक संगठित प्रयास था। यह वैश्विक आर्थिक शासन में सुधार की जटिलताओं और राष्ट्रों के बीच मौजूद गहरी असमानता को स्पष्ट रूप से उजागर करता है। यह अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंधों में समानता और न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में विकासशील देशों की साझा आकांक्षाओं और उनके संगठित कूटनीतिक प्रयासों का प्रतिबिंब है। यह वैश्विक सहयोग और सामूहिक समृद्धि की दिशा में एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य निर्धन राष्ट्रों को अंतरराष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली में समान और न्यायसंगत भागीदार बनाना है।

222. (C) इंडोनेशिया
1955 का ऐतिहासिक बांडुंग सम्मेलन इंडोनेशिया के बांडुंग शहर में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन ने एशिया और अफ्रीका के उन राष्ट्रों को एक साथ लाया जो हाल ही में उपनिवेशवाद से मुक्त हुए थे। इसका आयोजन इंडोनेशिया, भारत, पाकिस्तान, म्यांमार और श्रीलंका द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। इस सम्मेलन ने "बांडुंग की भावना" को जन्म दिया, जिसने संप्रभुता, समानता और आपसी सहयोग पर बल दिया। इसी सम्मेलन की सफलता ने बाद में गुटनिरपेक्ष आंदोलन और आधुनिक दक्षिण-दक्षिण सहयोग के लिए एक मजबूत नींव रखने का कार्य किया। यह वैश्विक राजनीति में विकासशील राष्ट्रों की सामूहिक आवाज और उनके स्वाभिमान का प्रतीक था। इसने अंतरराष्ट्रीय संबंधों में एक नए और न्यायपूर्ण वैश्विक दृष्टिकोण के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। बांडुंग सम्मेलन की महत्ता इसके द्वारा स्थापित विकासशील राष्ट्रों की एकजुटता और उपनिवेशवाद के विरुद्ध उनके साझा संघर्ष में निहित है, जिसने अंतरराष्ट्रीय कूटनीति को एक नई और न्यायपूर्ण दिशा प्रदान करने में निर्णायक भूमिका निभाई। यह दक्षिण-दक्षिण सहयोग के इतिहास का एक गौरवशाली अध्याय है।

223. (B) एक व्यापारिक भागीदार को दी गई कोई भी विशेष सुविधा अन्य सभी डब्ल्यूटीओ सदस्यों को दी जानी चाहिए।
'सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र' का सिद्धांत विश्व व्यापार संगठन के गैर-भेदभावपूर्ण व्यापारिक ढांचे का एक अनिवार्य स्तंभ है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी देश अपने व्यापारिक भागीदारों के बीच भेदभाव न करे। यदि एक देश किसी दूसरे देश को कम टैरिफ या व्यापारिक लाभ देता है, तो उसे वही लाभ स्वतः ही संगठन के सभी अन्य सदस्यों को भी देना पड़ता है। यह नियम अंतरराष्ट्रीय व्यापार में समानता और निष्पक्षता को बढ़ावा देता है और छोटे देशों को बड़े देशों के साथ समान अवसर प्रदान करता है। यह बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली में विश्वास बनाए रखने और व्यापारिक बाधाओं को दूर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कानूनी और नीतिगत सुधार है। यह वैश्विक बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा और समानता सुनिश्चित करने की दिशा में एक प्रभावी तंत्र प्रदान करता है जो अंतरराष्ट्रीय वाणिज्य के सुचारु संचालन में सहायक है। यह नियम व्यापारिक नीतियों में पारदर्शिता और निष्पक्षता को बढ़ावा देकर वैश्विक आर्थिक शासन में एक निर्णायक भूमिका निभाता है और बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को मजबूती प्रदान करता है।

224. (B) कुछ विकासशील देशों (जैसे, एशियाई टाइगर्स) की सफलता को समझाने में विफल रहता है।
निर्भरता सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना यह है कि यह उन विकासशील देशों की तीव्र आर्थिक वृद्धि को स्पष्ट नहीं कर पाता जिन्होंने वैश्विक पूंजीवादी व्यवस्था के भीतर रहकर ही सफलता प्राप्त की है। दक्षिण कोरिया, ताइवान और सिंगापुर जैसे राष्ट्रों ने इस सिद्धांत के विपरीत जाकर अपनी अर्थव्यवस्थाओं का सफलतापूर्वक आधुनिकीकरण किया। आलोचकों का तर्क है कि यह सिद्धांत आंतरिक कारकों और घरेलू नीतियों के महत्व की उपेक्षा करता है। यह विकासशील देशों को केवल एक असहाय पीड़ित के रूप में देखता है, जो उनकी अपनी क्षमता को पूरी तरह नकार देता है। यह अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंधों के भीतर मौजूद संरचनात्मक बाधाओं के बावजूद राष्ट्रों के आत्मनिर्भर विकास की संभावनाओं को स्पष्ट रूप से उजागर करता है। यद्यपि निर्भरता सिद्धांत वैश्विक असमानता के ऐतिहासिक कारणों का गहराई से विश्लेषण करता है, परंतु यह बदलती वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों और उभरती अर्थव्यवस्थाओं की सफलता के विविध आयामों को पूरी तरह से संबोधित करने में असमर्थ रहा है। यह विकास के विविध मॉडलों की महत्ता को रेखांकित करता है।

225. (C) श्रीलंका
श्रीलंका दक्षिण एशिया का एक महत्वपूर्ण देश है और यह सार्क का सदस्य है, न कि आसियान का। आसियान विशेष रूप से दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों का संगठन है, जिसमें इंडोनेशिया, सिंगापुर, वियतनाम और फिलीपींस जैसे राष्ट्र शामिल हैं। भौगोलिक और राजनीतिक रूप से श्रीलंका का झुकाव और सदस्यता दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय ढांचे के भीतर रही है। म्यांमार जैसे कुछ देश अपवाद हो सकते हैं जो दोनों क्षेत्रों की सीमा पर हैं, लेकिन श्रीलंका स्पष्ट रूप से सार्क की मूल संरचना और उसके क्षेत्रीय सहयोग का एक अभिन्न हिस्सा है। यह दक्षिण एशिया की क्षेत्रीय सीमाओं और कूटनीतिक पहचान को स्पष्ट करने वाला एक महत्वपूर्ण तथ्य है। सार्क का भौगोलिक केंद्र मुख्य रूप से दक्षिण एशिया है, जहाँ सदस्य राष्ट्र साझा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों के आधार पर सहयोग करते हैं। श्रीलंका की भूमिका क्षेत्रीय राजनीति और

NODIA

236. (B) 1971 के बांग्लादेश युद्ध से पूर्व भारत को सुरक्षा आश्वासन प्रदान किया।
1971 की भारत-सोवियत संधि भारत के सामरिक इतिहास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण समझौता था। इसने ऐसे समय में भारत को एक महाशक्ति का समर्थन दिलाया जब दक्षिण एशिया में युद्ध के बादल मंडरा रहे थे और अमेरिका एवं चीन पाकिस्तान के पक्ष में थे। इस संधि के कारण भारत को सोवियत संघ से सैन्य उपकरणों और कूटनीतिक सुरक्षा की गारंटी मिली, जिससे भारत आत्मविश्वास के साथ बांग्लादेश की मुक्ति में सहायता कर सका। यह संधि भारत की दूरदर्शी कूटनीति का एक उत्कृष्ट उदाहरण है जिसने क्षेत्र के भू-राजनीतिक मानचित्र को स्थाई रूप से बदल दिया। इसने क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को भारत के पक्ष में बनाए रखने में एक निर्णायक भूमिका निभाई। यद्यपि भारत गुटनिरपेक्ष था, परंतु इस समझौते ने देश के सामने खड़े तत्कालीन सुरक्षा खतरों को टालने और अपनी क्षेत्रीय अखंडता सुनिश्चित करने की दृढ़ इच्छाशक्ति का प्रमाण प्रस्तुत किया। यह अंतरराष्ट्रीय संबंधों में रणनीतिक साझेदारी और राष्ट्रीय हितों के सफल समन्वय को स्पष्ट करने वाला एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है जो भारत की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने में सहायक सिद्ध हुआ।

237. (B) ब्रेटन वुड्स आर्थिक प्रणाली।
नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की मांग मुख्य रूप से उन विकासशील देशों द्वारा की गई थी जो मानते थे कि ब्रेटन वुड्स संस्थानों (आईएमएफ और विश्व बैंक) द्वारा स्थापित वैश्विक आर्थिक ढांचा उनके प्रति पक्षपाती है। वे एक ऐसी प्रणाली चाहते थे जो उनके विकास की जरूरतों को समझे और उन्हें व्यापार में न्यायसंगत अवसर प्रदान करे। एनआईईओ का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय व्यापार के नियमों को बदलना और वैश्विक धन के वितरण में समानता लाना था। यह मौजूदा व्यवस्था में सुधार की एक संगठित और व्यापक मांग थी ताकि निर्धन राष्ट्रों की आर्थिक संप्रभुता को सुदृढ़ किया जा सके। यह अंतरराष्ट्रीय आर्थिक शासन में समानता और न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में विकासशील देशों की साझा आकांक्षाओं और उनके संगठित कूटनीतिक प्रयासों का प्रतिबिंब है। यद्यपि इसके लक्ष्यों की पूर्ण प्राप्ति चुनौतीपूर्ण रही, परंतु इसने वैश्विक आर्थिक संबंधों में न्याय की आवश्यकता पर एक वैश्विक बहस शुरू की। यह विकासशील राष्ट्रों की सामूहिक शक्ति और उनके आर्थिक स्वावलंबन के संघर्ष को ऐतिहासिक और सैद्धांतिक संदर्भ प्रदान करने वाली एक महत्वपूर्ण वैश्विक पहल थी।

238. (A) केवल 2
जी-77 का गठन वास्तव में विकासशील देशों द्वारा अपने सामूहिक आर्थिक हितों को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अधिक मजबूती से प्रस्तुत करने के लिए किया गया था। यह समूह आज भी संयुक्त राष्ट्र में विकासशील राष्ट्रों की सबसे बड़ी आवाज है। हालांकि, दक्षिण-दक्षिण सहयोग केवल सैन्य नहीं, बल्कि मुख्य रूप से आर्थिक और तकनीकी सहयोग का ढांचा है। उत्तर-दक्षिण संवाद अभी भी जारी है और इसने सभी विवादों को पूरी तरह नहीं सुलझाया है, बल्कि यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अतः, केवल जी-77 से संबंधित कथन ही पूर्णतः सत्य और सटीक है। यह विकासशील राष्ट्रों के बीच एकजुटता और समानता पर आधारित एक महत्वपूर्ण साझेदारी को दर्शाता है। जी-77 अंतरराष्ट्रीय आर्थिक शासन में विकासशील देशों के अधिकारों और उनकी न्यायसंगत भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और सक्रिय वैश्विक मंच है। यह सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने और विकसित देशों पर ऐतिहासिक निर्भरता को कम करने का संकल्प है, जो वैश्विक दक्षिण को सशक्त बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रहा है।

239. (B) निर्भरता सिद्धांत
निर्भरता सिद्धांत यह स्पष्ट करता है क्यों कुछ देश प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध होने के बावजूद आर्थिक रूप से पिछड़े रहते हैं। ऐसे देश अक्सर कच्चे माल के निर्यात पर निर्भर हो जाते हैं, जिसका मूल्य निर्मित वस्तुओं की तुलना में कम होता है। उनकी अर्थव्यवस्थाएं बाहरी शक्तियों द्वारा नियंत्रित की जाती हैं, जिससे वे औद्योगिक विकास के चक्र में प्रवेश नहीं कर पाते। यह स्थिति उन्हें विकसित देशों पर स्थाई रूप से निर्भर बना देती है, जो उनके संसाधनों का लाभ उठाते हैं। यह सिद्धांत वैश्विक व्यापार में मौजूद इस संरचनात्मक और शोषणकारी असंतुलन का गहराई से विश्लेषण करता है। यह वैश्विक स्तर पर धन और शक्ति के असमान वितरण के ऐतिहासिक और संरचनात्मक कारणों को उजागर करता है। विकासशील राष्ट्रों की आर्थिक स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए यह सिद्धांत वैश्विक आर्थिक शासन के ढांचे में मौलिक सुधार की आवश्यकता पर बल देता है। यह अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंधों में समानता और न्याय की मांग करने वाला एक महत्वपूर्ण सैद्धांतिक दृष्टिकोण है जो विकासशील राष्ट्रों के आर्थिक संघर्षों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है।

240. (C) P-4, Q-1, R-2, S-3
अंतरराष्ट्रीय संगठनों की स्थापना उनके विशिष्ट समझौतों और सम्मेलनों से जुड़ी हुई है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1994 के मराकेश समझौते के माध्यम से हुई थी। आसियान की नींव 1967 में बैंकॉक घोषणा द्वारा रखी गई थी, जो क्षेत्रीय सहयोग का आधार बनी। अमेरिकी राज्यों के संगठन का आधार 1948 का बोगोटा का चार्टर है। संयुक्त राष्ट्र संघ का औपचारिक जन्म 1945 के सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में चार्टर पर हस्ताक्षर के साथ हुआ था। ये ऐतिहासिक दस्तावेज इन संगठनों के लक्ष्यों, शक्तियों और उनकी संरचना को परिभाषित करने वाले अनिवार्य आधारभूत स्तंभ हैं। यह अंतरराष्ट्रीय कूटनीति और क्षेत्रीय एकीकरण के प्रयासों के क्रमिक विकास और उनकी वर्तमान प्रासंगिकता को तार्किक और व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने वाला एक अनिवार्य ऐतिहासिक प्रमाण है। ये संगठन अंतरराष्ट्रीय राजनीति और सुरक्षा प्रबंधन में एक निर्णायक और अपरिहार्य भूमिका निभाते हैं। यह कालक्रम वैश्विक सहयोग के बदलते स्वरूप और वैश्विक आर्थिक एवं सुरक्षा चुनौतियों के समाधान हेतु नए मंचों के निर्माण को स्पष्ट रूप से उजागर करता है, जो राष्ट्रों के सामूहिक प्रयासों का प्रतीक है।

NODIA

241. (A) आसियान (ASEAN)
आसियान के लिए अहस्तक्षेप का सिद्धांत एक दोधारी तलवार की तरह रहा है। यद्यपि इसने सदस्य देशों के बीच शांति बनाए रखी है, लेकिन जब किसी सदस्य देश के भीतर मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन होता है, तो यह सिद्धांत संगठन को प्रभावी कार्रवाई करने से रोकता है। म्यांमार जैसे देशों के संकट के दौरान आसियान की आलोचना अक्सर इसी कारण की जाती है कि वह अपने ही चार्टर के कारण हस्तक्षेप करने में असमर्थ रहता है। यह सिद्धांत संप्रभुता के सम्मान और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों के बीच एक निरंतर चलने वाला द्वंद्व और चुनौती पैदा करता रहता है। 'आसियान शैली' की यह अनूठी विशेषता क्षेत्रीय स्थिरता तो सुनिश्चित करती है, परंतु गंभीर आंतरिक संकटों के समय संगठन की भूमिका को सीमित कर देती है। यह क्षेत्रीय संगठनों के सम्मुख मौजूद संप्रभुता और मानवीय हस्तक्षेप के बीच के जटिल कूटनीतिक संतुलन को स्पष्ट रूप से उजागर करता है। आसियान के भविष्य के लिए इस सिद्धांत और वैश्विक मानवाधिकार उत्तरदायित्वों के बीच एक न्यायसंगत तालमेल बनाना एक अनिवार्य और महत्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है, जो इसकी प्रभावशीलता को निर्धारित करेगी।

242. (B) अंतरराष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय स्थिरता पर संवाद के लिए एक मंच प्रदान करना।
जी-20 का प्राथमिक लक्ष्य दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच नीतिगत समन्वय स्थापित करना है ताकि वैश्विक वित्तीय संकटों को रोका जा सके। यह समूह अंतरराष्ट्रीय वित्तीय वास्तुकला में सुधार और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है। इसमें विकसित और विकासशील देशों के प्रतिनिधि एक साथ बैठकर व्यापार, निवेश और जलवायु वित्तपोषण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करते हैं। यह एक अनौपचारिक लेकिन अत्यंत प्रभावशाली मंच है, जिसके निर्णय दुनिया भर की आर्थिक नीतियों और वैश्विक बाजारों की दिशा को गहराई से प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। 2008 के संकट के बाद जी-20 की भूमिका अपरिहार्य हो गई है, क्योंकि यह विकसित और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाकर वैश्विक चुनौतियों का सामूहिक समाधान खोजने के लिए एक प्रभावी और समावेशी मंच प्रदान करता है। यह वर्तमान वैश्विक आर्थिक शासन का एक अत्यंत प्रभावी माध्यम है जो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने और साझा आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए दुनिया की प्रमुख शक्तियों के बीच संवाद और सहयोग का वातावरण तैयार करता है।

243. (C) म्यांमार
सार्क की स्थापना के बाद, इसके पहले महासचिव के रूप में बांग्लादेश के कूटनीतिज्ञ अबुल अहसान को नियुक्त किया गया था। उन्होंने 1986 से 1989 तक इस पद पर कार्य किया और संगठन के शुरुआती ढांचे को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सार्क सचिवालय का नेतृत्व बारी-बारी से सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। बांग्लादेश द्वारा प्रथम महासचिव का पद संभालना इस क्षेत्रीय पहल को शुरू करने में उसकी अग्रणी भूमिका और उत्साह को भी दर्शाता है। यह पद संगठन के प्रशासनिक संचालन और सदस्य देशों के बीच समन्वय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। सार्क सचिवालय दक्षिण एशियाई राष्ट्रों के बीच सहयोग और संचार के मुख्य केंद्र के रूप में कार्य करता है। प्रथम महासचिव की नियुक्ति क्षेत्रीय एकीकरण और साझा विकास के प्रति दक्षिण एशियाई राष्ट्रों की प्रारंभिक प्रतिबद्धता का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर थी। यह संगठन की प्रशासनिक संरचना के क्रमिक विकास और क्षेत्रीय कूटनीति में सदस्य राष्ट्रों की सक्रिय भागीदारी को स्पष्ट रूप से उजागर करता है, जो दक्षिण एशिया के भविष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है।

244. (A) पेट्रोलियम उत्पादकों के लिए एक स्थिर और उचित आय सुनिश्चित करना।
ओपेक के सदस्य देश अपनी उत्पादन नीतियों का समन्वय इसलिए करते हैं ताकि वे वैश्विक बाजार में तेल की कीमतों को एक लाभकारी स्तर पर बनाए रख सकें। उनके बीच सहयोग का उद्देश्य आपसी प्रतिस्पर्धा को कम करना और सामूहिक रूप से बाजार को प्रभावित करना है। यह एकता उन्हें अंतरराष्ट्रीय तेल कंपनियों के दबाव से बचाती है और उनकी राष्ट्रीय आय को सुरक्षित करती है। ओपेक का मानना है कि तेल उत्पादक राष्ट्रों को उनके प्राकृतिक संसाधनों का उचित मूल्य मिलना चाहिए, जो उनकी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के विकास के लिए एक अनिवार्य वित्तीय आधार प्रदान करता है। ओपेक का मुख्य उद्देश्य तेल बाजारों को विनियमित और स्थिर करना है ताकि उत्पादकों और उपभोक्ताओं दोनों के हितों में संतुलन बना रहे। यह अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंधों में प्राकृतिक संसाधनों पर संप्रभु नियंत्रण और उत्पादकों के सामूहिक हितों की रक्षा का प्रतीक है। ओपेक की नीतियां वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा और विश्व की आर्थिक स्थिरता में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावी भूमिका निभाती हैं, जो इसे अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक निर्णायक खिलाड़ी बनाती हैं।

245. (C) आर्थिक और सामाजिक परिषद (ECOSOC)
आर्थिक और सामाजिक परिषद संयुक्त राष्ट्र का वह मुख्य अंग है जो लोगों के जीवन स्तर को सुधारने और सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। यह परिषद स्वास्थ्य, शिक्षा, मानवाधिकारों और सतत विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय सहयोग का समन्वय करती है। यह विभिन्न विशिष्ट एजेंसियों, जैसे यूनिसेफ और डब्ल्यूएचओ, के साथ मिलकर काम करती है ताकि वैश्विक स्तर पर गरीबी और असमानता को कम किया जा सके। ईकोसोक का कार्य मानवीय कल्याण और सामाजिक न्याय की दिशा में संयुक्त राष्ट्र के व्यापक प्रयासों को संगठित और दिशा प्रदान करना है। यह महासभा के साथ मिलकर आर्थिक और सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्य करता है और अंतरराष्ट्रीय समस्याओं के समाधान में सहायक होता है। ईकोसोक की महत्ता इसके द्वारा स्थापित वैश्विक विकास के समावेशी और न्यायसंगत ढांचे में निहित है, जो मानवता के बेहतर भविष्य के लिए एक अनिवार्य स्तंभ है। यह वैश्विक सहयोग के माध्यम से सामाजिक उत्थान और आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित करने की दिशा में संयुक्त राष्ट्र की अटूट प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करता है।

Downloaded from www.pdf.tube

246. (C) विकास वित्तपोषण और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार।
संयुक्त राष्ट्र के भीतर वैश्विक उत्तर (विकसित देश) और वैश्विक दक्षिण (विकासशील देश) के बीच सबसे अधिक तनाव विकास के लिए वित्तीय सहायता और सुरक्षा परिषद के लोकतांत्रिकरण को लेकर होता है। विकासशील देश अधिक आर्थिक सहायता और परिषद में बेहतर प्रतिनिधित्व की मांग करते हैं, जबकि विकसित देश अक्सर मौजूदा व्यवस्था और अपने प्रभाव को बनाए रखने का प्रयास करते हैं। ये बहसें अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में मौजूद शक्ति और धन के असमान वितरण को उजागर करती हैं। इन मुद्दों पर सहमति बनाना संगठन की भविष्य की प्रासंगिकता और विश्वसनीयता के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। सुरक्षा परिषद में सुधार के बिना संयुक्त राष्ट्र की लोकतांत्रिक वैधता और उसकी वैश्विक स्वीकार्यता को सुदृढ़ करना संभव नहीं है। यह अंतरराष्ट्रीय शासन प्रणाली में समानता और समावेशिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक अनिवार्य द्वंद्व है। इन संरचनात्मक मतभेदों को दूर करना और एक न्यायसंगत वैश्विक व्यवस्था का निर्माण करना 21वीं सदी के अंतरराष्ट्रीय संबंधों का एक प्रमुख लक्ष्य है, जो वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए निर्णायक है।

247. (C) सदस्य देशों की भुगतान करने की क्षमता।
संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट के लिए प्रत्येक सदस्य देश का अंशदान उसकी राष्ट्रीय आय और आर्थिक समृद्धि के आधार पर निर्धारित किया जाता है। इस सिद्धांत का अर्थ है कि अमीर और विकसित देश बजट का एक बड़ा हिस्सा वहन करते हैं, जबकि निर्धन और विकासशील देशों पर कम वित्तीय भार डाला जाता है। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि संगठन के पास अपने कार्यों के लिए पर्याप्त संसाधन हों और यह वित्तीय रूप से टिकाऊ बना रहे। यह अंतरराष्ट्रीय समुदाय के भीतर संसाधनों के न्यायसंगत वितरण और साझा जिम्मेदारी के विचार को भी मजबूती से परिलक्षित करता है। यह संगठन की वित्तीय पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है जो संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य राष्ट्रों की आर्थिक क्षमता के अनुरूप उनके योगदान को निर्धारित करता है। यह सिद्धांत अंतरराष्ट्रीय सहयोग में निष्पक्षता को बढ़ावा देता है और यह सुनिश्चित करता है कि वित्तीय बोझ का वितरण तर्कसंगत और न्यायपूर्ण हो। संयुक्त राष्ट्र के प्रभावी संचालन के लिए यह वित्तीय ढांचा एक अनिवार्य और सुदृढ़ आधार प्रदान करता है।

248. (B) भेदभावपूर्ण है और इसमें सार्वभौमिक निशस्त्रीकरण की समय सीमा सम्मिलित नहीं है।
भारत ने सीटीबीटी का विरोध इस आधार पर किया कि यह संधि वास्तविक और पूर्ण निशस्त्रीकरण की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाती। भारत का तर्क है कि यह संधि केवल नए परीक्षणों को रोकती है, लेकिन मौजूदा परमाणु शक्तियों को अपनी तकनीक सुधारने से नहीं रोकती। भारत के लिए कोई भी निशस्त्रीकरण संधि तभी स्वीकार्य हो सकती है जब वह सभी देशों पर समान रूप से लागू हो और इसमें हथियारों को पूरी तरह नष्ट करने की एक स्पष्ट समय सीमा हो। भारत इसे सुरक्षा के नाम पर महाशक्तियों के एकाधिकार को बनाए रखने का एक प्रयास मानता है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा और वैश्विक न्याय के सिद्धांतों के प्रति भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत का रुख सदैव सार्वभौमिक और समान निशस्त्रीकरण के पक्ष में रहा है, जो भेदभाव रहित हो। भारत का मानना है कि परमाणु मुक्त विश्व के लिए सभी राष्ट्रों को समान रूप से उत्तरदायी होना चाहिए और निशस्त्रीकरण की प्रक्रिया पारदर्शी एवं समयबद्ध होनी चाहिए। यह अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति भारत के नैतिक और रणनीतिक दृष्टिकोण का प्रमाण है।

249. (C) सांस्कृतिक प्रभाव, लोकतांत्रिक मूल्य और विदेशी सहायता।
'मृदु शक्ति' भारतीय कूटनीति का एक अत्यंत प्रभावशाली अंग है जो बल प्रयोग के बजाय आकर्षण और विश्वास के माध्यम से प्रभाव पैदा करता है। भारत की योग परंपरा, सिनेमा, संगीत और विविधतापूर्ण संस्कृति दुनिया भर में इसकी सकारात्मक छवि बनाने में मदद करती है। इसके साथ ही, एक मजबूत लोकतंत्र और विकासशील देशों को दी जाने वाली मानवीय सहायता भारत की नैतिक शक्ति को बढ़ाती है। यह शक्ति अंतरराष्ट्रीय संबंधों में भारत को एक "सौम्य शक्ति" के रूप में स्थापित करती है, जो सहयोग और शांति के माध्यम से वैश्विक स्तर पर अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाती है। भारतीय सभ्यता के अहिंसा, सहिष्णुता और वसुधैव कुटुंबकम के मूल्य कूटनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मृदु शक्ति का प्रभावी उपयोग भारत को एक जिम्मेदार और उभरती हुई वैश्विक शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित करता है, जो बिना किसी सैन्य दबाव के अंतरराष्ट्रीय जनमत को प्रभावित करने और साझा लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु संवाद का वातावरण तैयार करने में सक्षम है। यह आधुनिक अंतरराष्ट्रीय संबंधों में भारत की रणनीतिक श्रेष्ठता और उसके सांस्कृतिक गौरव का एक उत्कृष्ट प्रतीक है।

NODIA

250. (A) 4, 1, 2, 3
भारतीय विदेश नीति की प्रमुख पहलों का कालक्रम देश के ऐतिहासिक विकास और बदलती प्राथमिकताओं को दर्शाता है। जवाहरलाल नेहरू ने 1954 में पंचशील के साथ इसकी नींव रखी। इंदिरा गांधी के समय में 1972 में ऐतिहासिक शिमला समझौता हुआ। 1990 के दशक में पी.वी. नरसिम्हा राव ने 'लुक ईस्ट' नीति के माध्यम से आर्थिक नए द्वार खोले। अंत में, 1990 के दशक के उत्तरार्ध में आई.के. गुजराल ने पड़ोसियों के प्रति उदारता का सिद्धांत प्रस्तुत किया। यह विकास क्रम दर्शाता है कि कैसे प्रत्येक प्रधानमंत्री ने वैश्विक परिस्थितियों के अनुरूप भारत की कूटनीतिक दिशा को सफलतापूर्वक नई गति और विस्तार प्रदान किया। यह दर्शाता है कि भारत ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक हितों को सर्वोत्तम रूप से सुरक्षित रखने के लिए समय-समय पर अपनी रणनीतियों को कुशलतापूर्वक अनुकूलित किया है। यह विकासवादी यात्रा भारत को वैश्विक मंच पर एक विश्वसनीय, स्वतंत्र और न्यायप्रिय शक्ति के रूप में स्थापित करने में सहायक सिद्ध हुई है, जो आज की बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में अत्यंत प्रासंगिक है।

251. (B) एक न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण विश्व व्यवस्था का आदर्श।
भारतीय विदेश नीति सदैव अपने राष्ट्रीय हितों और वैश्विक नैतिक आदर्शों के बीच एक संतुलन बनाने का प्रयास करती रही है। भारत ने केवल अपनी सुरक्षा पर ही ध्यान नहीं दिया, बल्कि एक ऐसी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की वकालत की है जो न्याय, समानता और शांति पर आधारित हो। उपनिवेशवाद के विरोध से लेकर वैश्विक निशस्त्रीकरण के समर्थन तक, भारत के प्रयास इसी आदर्शवाद से प्रेरित रहे हैं। यह दोहरा दृष्टिकोण भारत को न केवल एक उभरती हुई शक्ति बनाता है, बल्कि इसे वैश्विक स्तर पर एक जिम्मेदार और शांतिप्रिय राष्ट्र के रूप में भी प्रतिष्ठित करता है। भारत का विश्वास अंतरराष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान और अहस्तक्षेप के सिद्धांतों में रहा है। यह राष्ट्रीय संप्रभुता और वैश्विक शांति के प्रति भारत की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करता है। भारतीय विदेश नीति के ये नैतिक आधार आज भी उसे अंतरराष्ट्रीय मंच पर एक स्वतंत्र और विश्वसनीय शक्ति के रूप में कार्य करने की अनुमति देते हैं, जो वैश्विक स्थिरता और सामूहिक कल्याण को सुदृढ़ करने के लिए समर्पित है।

252. (C) निकटतम पड़ोसी जिनके साथ उसके विशेष संबंध हैं।
नेपाल और भूटान के साथ भारत के संबंध भौगोलिक निकटता के साथ-साथ गहरे सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और सुरक्षा संबंधों पर आधारित हैं। इन देशों के साथ भारत की खुली सीमाएं और विशेष संधियां इस बात का प्रमाण हैं कि वे भारत के रणनीतिक हितों के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। भारत ने इन राष्ट्रों के विकास, विशेषकर बुनियादी ढांचे और ऊर्जा क्षेत्र में, निरंतर सहयोग प्रदान किया है। ये संबंध भारत की "पड़ोसी पहले" नीति की सफलता और क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने की इसकी दृढ़ प्रतिबद्धता को सबसे प्रभावी और स्पष्ट रूप से उजागर करते हैं। भारत और इन देशों के बीच के संबंध विश्वास और आपसी सहयोग पर आधारित एक अनूठी साझेदारी का उदाहरण हैं। यह द्विपक्षीय मैत्री क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के लिए आदर्श मानी जाती है और भारत के अपने पड़ोसियों के प्रति उदारता एवं रणनीतिक सहयोग के दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करती है। इन देशों की स्थिरता और प्रगति भारत की अपनी सुरक्षा और क्षेत्रीय एकीकरण के लक्ष्यों के साथ गहराई से जुड़ी हुई है, जो दक्षिण एशिया के भविष्य के लिए निर्णायक है।

253. (A) वैश्विक क्षेत्र में राजनीतिक शक्तियां आर्थिक परिणामों को कैसे आकार देती हैं और इसके विपरीत।
अंतरराष्ट्रीय संबंधों की राजनीतिक अर्थव्यवस्था एक ऐसा विषय है जो यह विश्लेषण करता है कि कैसे सरकारें और बाजार एक-दूसरे को प्रभावित करते हैं। राजनीतिक निर्णय, जैसे कि व्यापारिक प्रतिबंध या संधियां, सीधे तौर पर वैश्विक अर्थव्यवस्था की दिशा तय करते हैं। साथ ही, आर्थिक परिस्थितियां और संसाधनों की उपलब्धता राष्ट्रों की राजनीतिक शक्ति और उनकी विदेश नीति को भी गहराई से प्रभावित करती हैं। यह क्षेत्र धन और शक्ति के बीच के जटिल खेल को समझने के लिए अनिवार्य है। यह बताता है कि वैश्विक शासन में आर्थिक और राजनीतिक हित कैसे आपस में गुंथे हुए हैं। यह अंतरराष्ट्रीय संबंधों के वास्तविक आधारों का तार्किक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। यह राष्ट्रों की संप्रभुता और वैश्विक आर्थिक शासन के बीच के जटिल अंतर्संबंधों को स्पष्ट करने वाला एक महत्वपूर्ण सैद्धांतिक दृष्टिकोण है। यह बदलते हुए विश्व की जटिलताओं का विश्लेषण करने का एक प्रभावी माध्यम है, जो यह स्पष्ट करता है कि राष्ट्रीय समृद्धि की प्राप्ति हेतु राजनीति और अर्थशास्त्र का समन्वय अनिवार्य है।

254. (C) मौजूदा ब्रेटन वुड्स प्रणाली को सुदृढ़ करना।
नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था (NIEO) का मुख्य उद्देश्य ब्रेटन वुड्स प्रणाली को सुदृढ़ करना नहीं, बल्कि इसमें क्रांतिकारी सुधार करना या इसे पूरी तरह बदलना था। विकासशील देशों का मानना था कि मौजूदा प्रणाली विकसित राष्ट्रों के हितों की रक्षा करती है और उनके विकास में बाधक है। वे बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर कड़े नियंत्रण और कच्चे माल के लिए न्यायसंगत मूल्यों की मांग कर रहे थे। एनआईईओ का पूरा विचार ही वैश्विक आर्थिक शक्ति के पुनर्वितरण और निर्धन राष्ट्रों की आर्थिक संप्रभुता को बढ़ाने पर केंद्रित था, न कि पुरानी व्यवस्था को बनाए रखने पर। यह अंतरराष्ट्रीय आर्थिक शासन में समानता और न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में विकासशील देशों की साझा आकांक्षाओं और उनके संगठित कूटनीतिक प्रयासों का प्रतिबिंब है। यद्यपि इसके लक्ष्यों की पूर्ण प्राप्ति चुनौतीपूर्ण रही, परंतु इसने वैश्विक आर्थिक संबंधों में न्याय की आवश्यकता पर एक वैश्विक बहस शुरू की। यह विकासशील राष्ट्रों की सामूहिक शक्ति और उनके आर्थिक स्वावलंबन के संघर्ष को ऐतिहासिक और सैद्धांतिक संदर्भ प्रदान करने वाली एक महत्वपूर्ण वैश्विक पहल थी।

255. (B) उत्तर-दक्षिण संवाद की कथित विफलता और धीमी गति।
जब विकासशील देशों ने महसूस किया कि विकसित देशों के साथ उनकी वार्ताओं (उत्तर-दक्षिण संवाद) से कोई ठोस परिणाम नहीं निकल रहे हैं, तो उन्होंने एक-दूसरे के साथ सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया। इसी निराशा ने दक्षिण-दक्षिण सहयोग को एक नई प्रेरणा और गति प्रदान की। इन राष्ट्रों ने समझा कि सामूहिक आत्मनिर्भरता ही उनके विकास का एकमात्र स्थाई मार्ग है। एक-दूसरे के साथ व्यापार और तकनीक साझा करके वे अपनी शक्ति बढ़ा सकते हैं और विकसित देशों पर उनकी ऐतिहासिक निर्भरता को कम कर सकते हैं। यह एकता उनके आर्थिक स्वावलंबन का आधार बनी। दक्षिण-दक्षिण सहयोग विकासशील राष्ट्रों के बीच एकजुटता और आपसी सहायता का एक सशक्त माध्यम है। यह इस विचार पर आधारित है कि ये देश एक-दूसरे के अनुभवों और संसाधनों को साझा करके अपनी सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ा सकते हैं। यह सहयोग वैश्विक दक्षिण के सशक्तिकरण की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जो राष्ट्रों के बीच समानता और परस्पर सम्मान के सिद्धांतों पर आधारित है, जिससे वैश्विक विकास को एक नई और न्यायपूर्ण दिशा प्राप्त होती है।

256. (A) 'A' और 'R' दोनों सही हैं और 'R', 'A' की सही व्याख्या है।
डब्ल्यूटीओ की आलोचना अक्सर इस आधार पर की जाती है कि इसकी व्यापारिक नीतियां विकसित देशों की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के अनुकूल अधिक होती हैं। इसका मुख्य

Click Here to Buy book on Amazon

STUDYING FROM PDFs?

THINK AGAIN.

If you are studying only from PDFs,
you are wasting valuable time.

Research shows that learning from

PRINTED BOOKS has up to

4× HIGHER RETENTION

than studying from screens.

PRINT BOOK = BETTER MEMORY

PDF = LOWER RETENTION

Those who study from **PRINTED BOOKS**
move **AHEAD.**

Others are left **BEHIND**
in competition.

In competitive exams,
being average is not enough.

STAY ONE STEP AHEAD.

कारण पारस्परिकता का सिद्धांत है, जहाँ विकासशील देशों से भी वही रियायतें मांगी जाती हैं जो विकसित देश दे रहे हैं। छोटे देशों के लिए इन शर्तों को पूरा करना अक्सर उनके घरेलू उद्योगों के लिए हानिकारक होता है। यह विसंगति दर्शाती है कि कैसे वैश्विक नियम, यद्यपि वे कागजों पर समान दिखते हैं, व्यवहार में असमान आर्थिक स्तर वाले देशों के बीच अन्यायपूर्ण परिणाम पैदा कर सकते हैं। यह बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली में मौजूद शक्ति के असंतुलन और न्यायसंगत व्यापार नियमों की कमी को स्पष्ट रूप से उजागर करता है। विश्व व्यापार संगठन को अधिक समावेशी बनाने के लिए इसमें विकासशील राष्ट्रों की विशिष्ट परिस्थितियों और उनकी चुनौतियों को उचित महत्व देना अनिवार्य है। सुधार के बिना, वैश्विक व्यापार शासन की वैधता और निर्धन राष्ट्रों के प्रति इसकी निष्पक्षता पर निरंतर प्रश्नचिह्न लगे रहते हैं, जो अंतरराष्ट्रीय आर्थिक न्याय के लिए एक गंभीर चुनौती है।

257. (A) आर्थिक शोषण और निर्भरता।
नव-उपनिवेशवाद का मूल विचार यह है कि राजनीतिक वि-उपनिवेशीकरण ने केवल शासन का स्वरूप बदला है, उसकी शोषणकारी प्रकृति को नहीं। पूर्व औपनिवेशिक शक्तियां और अन्य विकसित राष्ट्र अभी भी अपनी आर्थिक शक्ति का उपयोग करके स्वतंत्र देशों के संसाधनों और बाजारों को नियंत्रित करते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के माध्यम से होने वाला यह नियंत्रण राष्ट्रों की आर्थिक स्वायत्तता को प्रभावी ढंग से समाप्त कर देता है। यह स्थिति सुनिश्चित करती है कि विकसित राष्ट्रों का लाभ बना रहे, जबकि विकासशील देश स्थाई रुप से उनकी पूंजी और तकनीक पर निर्भर बने रहें, जो आधुनिक शोषण का एक सूक्ष्म रुप है। नव-उपनिवेशवाद प्रत्यक्ष नियंत्रण के स्थान पर अप्रत्यक्ष माध्यमों से पूर्व उपनिवेशों का आर्थिक शोषण जारी रखने की एक सोची-समझी रणनीति है। यह स्वतंत्र राष्ट्रों की आर्थिक संप्रभुता और उनके स्वावलंबन के संघर्ष को प्रतिबिंबित करता है। यह अवधारणा अंतरराष्ट्रीय संबंधों में आर्थिक और सांस्कृतिक शक्ति के अप्रत्यक्ष रूपों को समझने के लिए अनिवार्य है, जो वैश्विक स्तर पर संप्रभुता की वास्तविक सीमाओं को गहराई से उजागर करती है।

258. (B) आसियान (ASEAN) - जकार्ता
आसियान का सचिवालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में स्थित है, जो इस क्षेत्रीय संगठन की प्रशासनिक गतिविधियों का मुख्य केंद्र है। जकार्ता में मुख्यालय होना दक्षिण-पूर्वी एशिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था में इंडोनेशिया की महत्वपूर्ण और केंद्रीय भूमिका को भी दर्शाता है। यह सचिवालय सदस्य देशों के बीच समन्वय स्थापित करने और विभिन्न क्षेत्रीय कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी करने का महत्वपूर्ण कार्य करता है। इसके विपरीत, सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है और ओपेक का वियना में, जो इन संगठनों के विशिष्ट भौगोलिक और रणनीतिक उद्देश्यों के अनुरूप निर्धारित किए गए हैं। आसियान सचिवालय सदस्य देशों के बीच सहयोग और संचार को सुगम बनाने में एक निर्णायक भूमिका निभाता है। जकार्ता की कूटनीतिक महत्ता और सचिवालय की संरचनात्मक मजबूती मिलकर क्षेत्रीय एकीकरण और सदस्य राष्ट्रों के बीच सुचारू संवाद सुनिश्चित करती है। यह क्षेत्रीय सहयोग और दक्षिण-पूर्व एशिया की एकजुटता को मजबूत करने के प्रयासों का केंद्र बिंदु है, जो संगठन की स्थिरता और उसके लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक अनिवार्य संस्थागत आधार प्रदान करता है।

259. (C) बिना स्थाई सचिवालय के एक अनौपचारिक मंच के रूप में कार्य करता है।
जी-20 की एक विशिष्ट विशेषता यह है कि इसका कोई स्थाई मुख्यालय या सचिवालय नहीं है, जैसा कि संयुक्त राष्ट्र में होता है। यह एक अनौपचारिक समूह के रूप में कार्य करता है जहाँ निर्णय आपसी संवाद और आम सहमति के माध्यम से लिए जाते हैं। इसकी अध्यक्षता और प्रशासनिक जिम्मेदारी प्रत्येक वर्ष एक सदस्य देश से दूसरे सदस्य देश को हस्तांतरित होती है। यह लचीली संरचना जी-20 को बदलती वैश्विक परिस्थितियों के प्रति अधिक अनुकूल और गतिशील बनाती है। यह किसी भी स्थाई नौकरशाही के दबाव के बिना प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच प्रभावी नीतिगत समन्वय सुनिश्चित करता है। जी-20 की अध्यक्षता और 'ट्रोइका' प्रणाली निरंतरता बनाए रखने में सहायक होती है, जहाँ वर्तमान, पिछला और आगामी अध्यक्ष मिलकर कार्य करते हैं। यह अनौपचारिक ढांचा सदस्य देशों को जटिल आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर अधिक लचीलेपन के साथ चर्चा करने और सामूहिक समाधान खोजने का अवसर प्रदान करता है। यह वर्तमान वैश्विक आर्थिक शासन में जी-20 की प्रभावशीलता और इसकी बढ़ती प्रासंगिकता का एक प्रमुख और अद्वितीय कारण है।

260. (B) सुरक्षा संवाद और विश्वास-निर्माण।
आसियान क्षेत्रीय मंच का प्राथमिक उद्देश्य एशिया-प्रशांत क्षेत्र में शांति और सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक बहुपक्षीय मंच प्रदान करना है। यह एक ऐसी संस्था है जहाँ सदस्य देश और बाहरी सहयोगी राष्ट्र निवारक कूटनीति के माध्यम से आपसी गलतफहमियों को दूर करने और विश्वास बनाने का प्रयास करते हैं। एआरएफ की कार्यप्रणाली 'आसियान शैली' पर आधारित है, जो आम सहमति और अहस्तक्षेप को प्राथमिकता देती है। यह मंच क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने और संभावित संघर्षों को टालने के लिए एक अनिवार्य और महत्वपूर्ण कूटनीतिक ढांचा प्रदान करता है। इसमें आसियान सदस्यों के अतिरिक्त कई बड़ी वैश्विक शक्तियां भी भाग लेती हैं, जो इसे एशिया-प्रशांत की सुरक्षा व्यवस्था का एक समावेशी और प्रभावी स्तंभ बनाती हैं। मंच का मुख्य जोर राजनीतिक और सुरक्षा चिंताओं पर संवाद को बढ़ावा देने और दीर्घकालिक शांति सुनिश्चित करने पर है। यह क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों का सामूहिक समाधान खोजने और सदस्य राष्ट्रों के बीच कूटनीतिक संबंधों को सुदृढ़ करने की दिशा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और सफल एशियाई प्रयास सिद्ध हुआ है।

261. (C) ओपेक (OPEC)
1973 के तेल संकट ने ओपेक को वैश्विक राजनीति के केंद्र में ला खड़ा किया और इसे दुनिया के सबसे प्रभावशाली संगठनों में से एक बना दिया। तेल की कीमतों में भारी वृद्धि करके, ओपेक देशों ने यह सिद्ध कर दिया कि उनके पास वैश्विक अर्थव्यवस्था

NODIA

और अंतरराष्ट्रीय संगठनों में सक्रिय भागीदारी के माध्यम से किया जाता है। कूटनीति का उद्देश्य युद्ध के बिना विवादों को सुलझाना और भारत के विकास के लिए एक अनुकूल वैश्विक वातावरण तैयार करना है। इसमें विदेशों में भारत की छवि को बेहतर बनाना और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश के दृष्टिकोण को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना भी शामिल है। एक सफल कूटनीति ही भारत को एक जिम्मेदार और उभरती हुई महाशक्ति के रूप में स्थापित करने का सबसे अनिवार्य और महत्वपूर्ण आधार है। कूटनीति वह अनिवार्य माध्यम है जिसके द्वारा भारत अपने विदेश नीति के लक्ष्यों और सिद्धांतों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्रियान्वित करता है। यह बातचीत और प्रतिनिधित्व का एक सूक्ष्म अभ्यास है जो राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए वैश्विक चुनौतियों का सामूहिक समाधान खोजने का प्रयास करता है। भारत की कूटनीतिक सफलता क्षेत्रीय शांति, रणनीतिक स्वायत्तता और एक न्यायपूर्ण विश्व व्यवस्था के निर्माण के प्रति उसकी अडिग प्रतिबद्धता पर आधारित है, जो राष्ट्रहितों और वैश्विक उत्तरदायित्वों के बीच एक आदर्श तालमेल सुनिश्चित करती है।

281. (B) बाहरी हस्तक्षेप के बिना द्विपक्षीय रूप से मुद्दों का समाधान।
1972 का शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के संबंधों में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर था जिसने यह स्पष्ट रूप से स्थापित किया कि कश्मीर सहित सभी विवादों को केवल द्विपक्षीय बातचीत के माध्यम से ही हल किया जाएगा। इसमें किसी भी तीसरे पक्ष या अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता की गुंजाइश को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया था। इस समझौते ने शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व और एक-दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान पर बल दिया। भारत के लिए शिमला समझौता आज भी पाकिस्तान के साथ संबंधों का मूल आधार बना हुआ है, जो यह सुनिश्चित करता है कि आपसी मुद्दों का समाधान केवल आपसी समझ और सीधा संवाद से ही निकाला जाए। यह दक्षिण एशियाई क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक दस्तावेज है। शिमला समझौते ने दोनों देशों के बीच संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में एक गंभीर पहल की थी, जिसने यह सिद्धांत स्थापित किया कि बिना किसी बाहरी प्रभाव के ही स्थाई शांति प्राप्त की जा सकती है। भारत की यह नीति रणनीतिक स्वायत्तता और द्विपक्षीय कूटनीति के प्रति उसकी अडिग प्रतिबद्धता का प्रमाण है, जो क्षेत्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए एक सुदृढ़ और विश्वसनीय ढांचा प्रदान करती है।

282. (B) रणनीतिक स्वायत्तता (Strategic Autonomy)
"रणनीतिक स्वायत्तता" आधुनिक समय में भारत की उस दृढ़ इच्छाशक्ति को दर्शाती है जिसके तहत वह किसी भी बाहरी दबाव या गठबंधन के बिना अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार निर्णय लेता है। यह गुटनिरपेक्षता के मूल विचार का ही एक विकसित और व्यावहारिक संस्करण है, जो भारत को एक बहुध्रुवीय विश्व में विभिन्न शक्तियों के साथ स्वतंत्र रूप से जुड़ने की अनुमति देता है। इसके माध्यम से भारत अपनी सुरक्षा और आर्थिक नीतियों को किसी एक शक्ति गुट के अधीन होने से बचाता है। यह दृष्टिकोण भारत को अंतरराष्ट्रीय मंच पर एक स्वतंत्र, विश्वसनीय और प्रभावशाली खिलाड़ी के रूप में अपनी भूमिका निभाने की पूरी स्वाधीनता और शक्ति प्रदान करता है। रणनीतिक स्वायत्तता आज भारत की विदेश नीति की एक प्रमुख विशेषता है, जो उसे अमेरिका, रूस और चीन जैसी विभिन्न शक्तियों के साथ अपने हितों के आधार पर संतुलित संबंध बनाए रखने में सक्षम बनाती है। यह राष्ट्रीय संप्रभुता और वैश्विक शांति के प्रति भारत की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करता है। यह नीति की गतिशीलता और बदलती वैश्विक परिस्थितियों के अनुरूप भारत की कूटनीतिक स्वाधीनता और उसके वैश्विक लक्ष्यों की प्रभावी प्राप्ति का एक अनिवार्य आधार है, जो भारत को एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित करता है।

283. (A) सोवियत संघ का पतन और नए आर्थिक भागीदारों की आवश्यकता।
1990 के दशक की शुरुआत में सोवियत संघ के विघटन के बाद भारत ने महसूस किया कि उसकी विदेश नीति में बदलाव अनिवार्य है। सोवियत संघ भारत का एक प्रमुख आर्थिक और सामरिक सहयोगी था, जिसके जाने से एक खालीपन पैदा हो गया था। इसी समय भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को भी उदार बनाया, जिससे उसे नए बाजारों की तलाश करने की आवश्यकता हुई। दक्षिण-पूर्व एशिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं ने भारत के लिए एक नया अवसर प्रस्तुत किया। इसी पृष्ठभूमि में 'लुक ईस्ट' नीति का जन्म हुआ, जिसने भारत के कूटनीतिक और आर्थिक ध्यान को सोवियत संघ से हटाकर पूर्व की ओर सफलतापूर्वक केंद्रित किया। यह नीति की गतिशीलता और बदलती वैश्विक परिस्थितियों के अनुरूप भारत की कूटनीतिक दिशा को नया विस्तार प्रदान करने का एक सफल प्रयास था। इसने भारत को एशिया-प्रशांत क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण आर्थिक और रणनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित करने में मदद की। 'लुक ईस्ट' नीति न केवल आर्थिक सहयोग पर केंद्रित थी, बल्कि इसने क्षेत्रीय एकीकरण और दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्रों के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी को भी सुदृढ़ किया, जो वर्तमान में 'एक्ट ईस्ट' नीति के रूप में और अधिक सक्रिय और परिणाम-उन्मुख हो गई है।

284. (B) अमीर, औद्योगिक राष्ट्र और निर्धन, विकासशील राष्ट्र।
"उत्तर-दक्षिण संवाद" शब्द का उपयोग अंतरराष्ट्रीय संबंधों में दुनिया के आर्थिक रूप से संपन्न उत्तरी राष्ट्रों और गरीब दक्षिणी राष्ट्रों के बीच के अंतर्विरोधों को दर्शाने के लिए किया जाता है। 'उत्तर' में मुख्य रूप से पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका के विकसित देश शामिल हैं, जबकि 'दक्षिण' में एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के विकासशील देश आते हैं। यह संवाद वैश्विक धन के असमान वितरण, व्यापारिक बाधाओं और विकास के अवसरों पर केंद्रित रहता है। इसका उद्देश्य इन दो समूहों के बीच की गहरी आर्थिक और तकनीकी खाई को कम करके एक अधिक न्यायसंगत और संतुलित वैश्विक समाज का निर्माण करना है। यह अंतरराष्ट्रीय आर्थिक शासन में समानता और न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में विकासशील देशों की साझा आकांक्षाओं और उनके संगठित प्रयासों का प्रतिबिंब है। यद्यपि इसके लक्ष्यों की पूर्ण प्राप्ति चुनौतीपूर्ण रही है, परंतु इसने वैश्विक आर्थिक संबंधों में न्याय की आवश्यकता पर एक

Downloaded from www.pdf.tube

स्वतंत्रता के बाद सदैव किसी भी सैन्य गठबंधन, जैसे सीटो या सेंटो, में शामिल होने का कड़ा विरोध किया है ताकि वह अपनी स्वायत्तता बनाए रख सके। भारत का मानना रहा है कि ऐसे गठबंधन क्षेत्र में तनाव बढ़ाते हैं और विकास के मार्ग में बाधक होते हैं। ये दो विशेषताएं भारत को वैश्विक मंच पर एक स्वतंत्र और न्यायप्रिय शक्ति के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान प्रदान करने में सहायक रही हैं। रणनीतिक स्वायत्तता और शांतिपूर्ण संवाद के प्रति भारत की यह दीर्घकालिक प्रतिबद्धता आज भी उसकी कूटनीतिक प्राथमिकताओं का मूल आधार बनी हुई है। भारत ने सदैव अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए सैन्य गुटों से दूरी बनाए रखी और उपनिवेशवाद के विरोध को अपनी नीति का केंद्र बनाया। यह अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति भारत के नैतिक दृष्टिकोण का प्रमाण है, जो वैश्विक दक्षिण के राष्ट्रों के बीच उसकी नेतृत्वकारी भूमिका और उसके स्वाभिमान को सुदृढ़ करता है।

267. (B) इसके भारत की अपनी सुरक्षा और स्थिरता के लिए प्रत्यक्ष निहितार्थ हैं।
भारत की विदेश नीति में पड़ोसियों के साथ संबंध सर्वोपरि हैं क्योंकि दक्षिण एशिया में होने वाली कोई भी घटना भारत को सीधे प्रभावित करती है। अस्थिर पड़ोस न केवल सुरक्षा खतरे पैदा करता है, बल्कि भारत के आर्थिक विकास की गति को भी धीमा कर सकता है। सीमा पार आतंकवाद, शरणार्थी संकट और क्षेत्रीय विवाद ऐसी चुनौतियां हैं जिनका समाधान केवल पड़ोसी देशों के साथ मजबूत सहयोग के माध्यम से ही संभव है। इसलिए, 'पड़ोसी पहले' की नीति भारत के लिए कोई विकल्प नहीं, बल्कि उसकी अपनी अखंडता और समृद्धि सुनिश्चित करने की एक अनिवार्य रणनीतिक आवश्यकता है। भारत का मानना है कि उसके अपने विकास और सुरक्षा के लिए एक मजबूत और सहयोगी पड़ोस अनिवार्य है। इस नीति के तहत, भारत व्यापार, कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे के विकास में सक्रिय भागीदारी करके द्विपक्षीय विश्वास को मजबूत करने का निरंतर प्रयास करता है। क्षेत्रीय स्थिरता और सहयोग सुनिश्चित करने के लिए भारत की ओर से पड़ोसी राष्ट्रों के प्रति उदारता और परस्पर सम्मान की भावना प्रदर्शित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो दक्षिण एशिया के भविष्य के लिए एक निर्णायक रणनीतिक आधार है।

268. (C) 1965 भारत-पाकिस्तान युद्ध
1966 का ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 के भीषण युद्ध की समाप्ति के बाद संपन्न हुआ था। सोवियत संघ ने इस समझौते में एक निष्पक्ष मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी, जिसने दोनों देशों को बातचीत की मेज पर लाने में सफलता प्राप्त की। समझौते का मुख्य उद्देश्य युद्ध से पूर्व की सीमाओं पर लौटना और भविष्य के विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने का संकल्प लेना था। यह समझौता शीत युद्ध के दौरान दक्षिण एशिया में शांति स्थापित करने के लिए किए गए सबसे महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक प्रयासों में से एक माना जाता है, जिसने क्षेत्र को अस्थाई स्थिरता प्रदान की। ताशकंद समझौते ने दोनों देशों के बीच संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में एक गंभीर पहल की थी, यद्यपि इसके पूर्ण कार्यान्वयन में चुनौतियां बनी रहीं। यह अंतरराष्ट्रीय संबंधों में मध्यस्थता और संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के महत्व को रेखांकित करने वाला एक ऐतिहासिक उदाहरण है। भारत के लिए यह समझौता अपनी सीमाओं की रक्षा और क्षेत्रीय शांति के प्रति उसकी अडिग प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिसने दक्षिण एशिया के कूटनीतिक इतिहास में एक निर्णायक भूमिका निभाई।

269. (C) बातचीत (Negotiation)
बातचीत या वार्ता कूटनीति का सबसे सशक्त और प्राथमिक साधन है जिसके द्वारा राष्ट्र युद्ध के बिना अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इसमें विभिन्न पक्षों के बीच संवाद स्थापित करना, समझौतों पर हस्ताक्षर करना और आपसी असहमति के बिंदुओं को हल करना शामिल है। एक कुशल बातचीत संघर्षों को टालने और दीर्घकालिक सहयोग के द्वार खोलने में सहायक होती है। यह अंतरराष्ट्रीय संबंधों की वह कला है जो धैर्य, तर्क और आपसी समझ पर आधारित है। कूटनीति का मूल उद्देश्य राष्ट्रों के बीच टकराव को कम करके एक न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व का वातावरण तैयार करना है। वार्ता के माध्यम से राष्ट्र अपने हितों की रक्षा करते हुए वैश्विक चुनौतियों का सामूहिक समाधान खोजते हैं। यह अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में शांति और सहयोग बनाए रखने का एक अनिवार्य और प्रभावी माध्यम है। कूटनीति की सफलता राष्ट्र की प्रतिष्ठा और उसके वैश्विक प्रभाव को सुदृढ़ करती है, जिससे राष्ट्रहितों और वैश्विक लक्ष्यों के बीच एक न्यायसंगत तालमेल बनाना संभव होता है। यह अंतरराष्ट्रीय राजनीति के जटिल अंतर्संबंधों को प्रबंधित करने का सबसे परिष्कृत और शांतिपूर्ण रणनीतिक उपकरण है।

270. (B) P-3, Q-1, R-4, S-2
अंतरराष्ट्रीय राजनीति और विकास के विभिन्न सिद्धांतों का संबंध महत्वपूर्ण विचारकों और नेताओं से है। राउल प्रेबिश निर्भरता सिद्धांत के प्रमुख प्रणेता माने जाते हैं, जिन्होंने वैश्विक आर्थिक असमानता का विश्लेषण किया। क्वामे न्क्रूमा ने नव-उपनिवेशवाद की अवधारणा के माध्यम से स्वतंत्र राष्ट्रों पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण की चेतावनी दी। आई.के. गुजराल ने पड़ोसियों के प्रति उदारता का अपना प्रसिद्ध 'गुजराल सिद्धांत' प्रस्तुत किया। विली ब्रांट ने उत्तर-दक्षिण संवाद की आवश्यकता पर बल दिया, जो वैश्विक स्तर पर धनी और निर्धन देशों के बीच सहयोग की दिशा में एक बड़ा कदम था। ये सभी सिद्धांत और विचार अंतरराष्ट्रीय संबंधों के बदलते स्वरूप को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण आधार प्रदान करते हैं। ये अवधारणाएं राष्ट्रों के बीच आर्थिक और सुरक्षा संबंधों को प्रबंधित करने के विभिन्न साधनों और ऐतिहासिक मील के पत्थरों को स्पष्ट करती हैं। यह अंतरराष्ट्रीय कूटनीति और क्षेत्रीय एकीकरण के प्रयासों के क्रमिक विकास का एक व्यवस्थित सारांश है। प्रत्येक विचारक और नेता ने अपने समय की चुनौतियों के अनुरूप अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में सुधार और न्याय स्थापित करने के लिए मौलिक और प्रभावशाली रणनीतिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किए।

NODIA

को प्रभावित करने की अपार शक्ति है। इस घटना ने विकसित राष्ट्रों की तेल पर निर्भरता को उजागर किया और ऊर्जा सुरक्षा को अंतरराष्ट्रीय एजेंडे में सबसे ऊपर ला दिया। इसने ओपेक को न केवल एक आर्थिक बल्कि एक अत्यंत शक्तिशाली राजनीतिक शक्ति के रूप में भी स्थापित किया, जिसकी आवाज विश्व भर में सुनी गई। यह प्राकृतिक संसाधनों पर संप्रभु नियंत्रण और अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल उत्पादक विकासशील देशों की सामूहिक शक्ति का प्रतीक था। ओपेक की इस कार्रवाई ने वैश्विक आर्थिक शक्ति संतुलन में एक ऐतिहासिक बदलाव लाया, जिसने विकसित और विकासशील राष्ट्रों के बीच के संबंधों को पुनर्परिभाषित किया। ऊर्जा राजनीति और वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिरता में ओपेक की भूमिका तब से अत्यंत महत्वपूर्ण और निर्णायक बनी हुई है, जो अंतरराष्ट्रीय संबंधों में संसाधनों की रणनीतिक महत्ता को स्पष्ट करती है।

262. (A) राष्ट्रों के कार्यों में तालमेल बिठाने के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य करना।
संयुक्त राष्ट्र का एक प्राथमिक और अनिवार्य लक्ष्य यह है कि वह विभिन्न देशों के बीच आपसी सहयोग और समन्वय के लिए एक साझा वैश्विक मंच प्रदान करे। चार्टर के अनुसार, इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और विकास की चुनौतियों का सामूहिक रूप से समाधान ढूंढना है। यह राष्ट्रों को एक साथ लाता है ताकि वे अपने साझा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मिलकर कार्य कर सकें और विवादों को शांतिपूर्ण संवाद के माध्यम से हल कर सकें। यह केंद्र के रूप में कार्य करना ही संयुक्त राष्ट्र को वैश्विक शासन की आधारशिला और अंतरराष्ट्रीय सहयोग का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ बनाता है। यह संगठन मानवता के बेहतर और सुरक्षित भविष्य के लिए एक वैश्विक संकल्प का प्रतीक है। विभिन्न अंगों के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र वैश्विक नीतियों के कार्यान्वयन और अंतरराष्ट्रीय कानून के शासन को बनाए रखने में एक निर्णायक भूमिका निभाता है। राष्ट्रों के कार्यों में सामंजस्य स्थापित करने का यह कार्य ही संगठन की प्रभावशीलता और उसकी वैश्विक स्वीकार्यता को सुदृढ़ करने का आधार है, जो 21वीं सदी की जटिल चुनौतियों का सामना करने के लिए अपरिहार्य है।

263. (C) अपने प्रस्तावों के कार्यान्वयन के लिए सदस्य देशों की राजनीतिक इच्छाशक्ति पर निर्भरता।
संयुक्त राष्ट्र की एक बड़ी सीमा यह है कि इसके पास अपने प्रस्तावों को लागू करने के लिए अपनी कोई स्वतंत्र सेना या प्रवर्तन बल नहीं है। यह पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि सदस्य देश इसके निर्णयों का सम्मान करेंगे और उन्हें लागू करने के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करेंगे। अक्सर, जब शक्तिशाली राष्ट्रों के हित प्रभावित होते हैं, तो वे संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों की अनदेखी करते हैं, जिससे संगठन की प्रभावशीलता कम हो जाती है। यह निर्भरता अंतरराष्ट्रीय कानून के शासन को बनाए रखने और वैश्विक शांति सुनिश्चित करने के संगठन के प्रयासों में एक स्थाई बाधा बनी रहती है। संयुक्त राष्ट्र की प्रवर्तन शक्ति सदस्य राष्ट्रों की सामूहिक राजनीतिक इच्छाशक्ति और उनके आपसी सहयोग पर आधारित है। जब राष्ट्रहित वैश्विक लक्ष्यों के विरुद्ध होते हैं, तो संगठन पंगु हो जाता है, जो अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन की संरचनात्मक दुर्बलता को उजागर करता है। सुधार के बिना संयुक्त राष्ट्र की लोकतांत्रिक वैधता और उसकी प्रवर्तन क्षमता को सुदृढ़ करना संभव नहीं है, जो वैश्विक न्याय और शांति के लिए एक निरंतर बनी रहने वाली चुनौती है।

264. (D) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।
संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना एक अभिनव और लचीला तंत्र है जो शीत युद्ध के दौरान संघर्षों को नियंत्रित करने के लिए विकसित हुआ था। इसके तीन मूल स्तंभ हैं: मेजबान की सहमति, पूर्ण निष्पक्षता और केवल आत्मरक्षा में बल का प्रयोग। हालांकि, इसका विस्तृत विवरण संयुक्त राष्ट्र चार्टर में मूल रूप से नहीं दिया गया था, बल्कि इसे एक कार्यात्मक उपकरण के रूप में बाद में विकसित किया गया। यह संघर्ष प्रवर्तन की तुलना में एक शांति रक्षक प्रयास अधिक है, जो युद्ध विराम को बनाए रखने और राजनीतिक समाधान के लिए सुरक्षित वातावरण तैयार करने का कार्य करता है। शांति सैनिकों को उनकी नीली टोपियों के कारण 'ब्लू हेलमेट' कहा जाता है, जो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राष्ट्रों की साझा प्रतिबद्धता का प्रतीक हैं। यह वैश्विक शांति स्थापना के मानवीय मिशन का एक आधारभूत और सफल मॉडल सिद्ध हुआ है। यद्यपि चार्टर में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं है, परंतु यह अंतरराष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण प्रबंधन के लिए संयुक्त राष्ट्र का सबसे प्रभावी और सम्मानित साधन बन गया है, जो वैश्विक स्थिरता में निर्णायक भूमिका निभाता है।

265. (B) संयुक्त राष्ट्र के एजेंडे, मानदंडों और कार्यों को अपने हितों के साथ संरेखित करने के लिए प्रभावित करना।
संयुक्त राष्ट्र के भीतर शक्ति संघर्ष वास्तव में इस बात की प्रतिस्पर्धा है कि वैश्विक नीतियों और नियमों को कौन नियंत्रित करेगा। विभिन्न राष्ट्र इस मंच का उपयोग अपनी 'मृदु शक्ति' प्रदर्शित करने और अंतरराष्ट्रीय राय को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए करते हैं। वे चाहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र की प्राथमिकताएं और उसके द्वारा पारित प्रस्ताव उनके राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक हितों के अनुकूल हों। यह कूटनीतिक संघर्ष दर्शाता है कि संयुक्त राष्ट्र केवल एक सेवा प्रदाता नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति राजनीति का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और सक्रिय अखाड़ा है जहाँ भविष्य के वैश्विक मानदंडों का निर्धारण होता है। राष्ट्र अपने प्रभाव का उपयोग करके बजट, नियुक्तियों और शांति अभियानों की दिशा तय करने का प्रयास करते हैं। यह बहुपक्षीय कूटनीति का एक अनिवार्य हिस्सा है जहाँ राष्ट्रहित और वैश्विक लक्ष्यों के बीच संतुलन बनाने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। संयुक्त राष्ट्र में प्रभावी कूटनीति राष्ट्र की प्रतिष्ठा और उसके वैश्विक प्रभाव को सुदृढ़ करती है, जो अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में उसकी निर्णायक भूमिका को सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और रणनीतिक साधन है।

266. (A) केवल 1 और 2
भारतीय विदेश नीति के मूल सिद्धांतों में पंचशील और गुटनिरपेक्षता सबसे प्रमुख हैं, जो अंतरराष्ट्रीय संबंधों में स्वतंत्रता और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की वकालत करते हैं। भारत ने

Click Here to Buy book on Amazon

को दर्शाता है। जोफ़ान ने दक्षिण-पूर्व एशिया में एक शांतिपूर्ण और स्वतंत्र वातावरण तैयार करने में निर्णायक भूमिका निभाई, जिसने सदस्य राष्ट्रों को बिना किसी बाहरी दबाव के अपने आर्थिक और सामाजिक विकास पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर प्रदान किया। यह क्षेत्रीय एकीकरण और रणनीतिक स्वायत्तता का एक सफल एशियाई उदाहरण है।

276. (C) इसके पास कानूनी रुप से बाध्यकारी चार्टर और प्रवर्तन शक्तियां हैं।
जी-20 की एक प्रमुख विशेषता यह है कि यह एक औपचारिक अंतरराष्ट्रीय संगठन नहीं है, बल्कि यह प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच संवाद का एक अनौपचारिक मंच है। इसके पास संयुक्त राष्ट्र या डब्ल्यूटीओ की तरह कोई कानूनी रूप से बाध्यकारी चार्टर या नियमों को लागू करने वाली प्रवर्तन शक्तियां नहीं हैं। इसके निर्णय केवल सदस्य देशों की स्वैच्छिक प्रतिबद्धताओं पर आधारित होते हैं। यद्यपि इन निर्णयों का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, परंतु वे तकनीकी रूप से किसी भी देश पर कानूनन लागू नहीं किए जा सकते। यह लचीलापन ही जी-20 को विभिन्न आर्थिक हितों के बीच समन्वय स्थापित करने का अवसर प्रदान करता है। जी-20 की अध्यक्षता और 'ट्रोइका' प्रणाली निरंतरता बनाए रखने में सहायक होती है, जो इसे एक गतिशील और समावेशी मंच बनाती है। इसकी अनौपचारिक प्रकृति सदस्य देशों को जटिल आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर अधिक लचीलेपन के साथ चर्चा करने और सामूहिक समाधान खोजने का अवसर प्रदान करती है। यह वर्तमान वैश्विक आर्थिक शासन में जी-20 की प्रभावशीलता और उसकी बढ़ती प्रासंगिकता का एक प्रमुख कारण है, जो विकसित और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाकर वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए एक प्रभावी मंच प्रदान करता है।

277. (C) जर्मन
संयुक्त राष्ट्र में कार्य के सुचारु संचालन के लिए छह आधिकारिक भाषाएं निर्धारित की गई हैं: अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनिश। जर्मन भाषा, यद्यपि एक महत्वपूर्ण वैश्विक भाषा है, लेकिन यह संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं में शामिल नहीं है। इन भाषाओं का चयन संगठन के गठन के समय की ऐतिहासिक परिस्थितियों और वैश्विक प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखकर किया गया था। महासभा के सभी आधिकारिक दस्तावेजों और बहसों का अनुवाद इन छह भाषाओं में किया जाना अनिवार्य होता है ताकि सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि प्रभावी ढंग से संगठन की कार्यवाही में भाग ले सकें और उसे समझ सकें। यह भाषाई विविधता संयुक्त राष्ट्र की समावेशी प्रकृति और उसके वैश्विक स्वरूप को प्रतिबिंबित करती है। आधिकारिक भाषाओं का यह प्रावधान अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है और सभी सदस्य राष्ट्रों की समान भागीदारी को सुगम बनाता है। यद्यपि समय-समय पर अन्य भाषाओं को जोड़ने की मांग उठती रहती है, परंतु वर्तमान व्यवस्था संयुक्त राष्ट्र की प्रशासनिक संरचना और उसके सुचारु संचालन का एक अनिवार्य आधार बनी हुई है, जो अंतरराष्ट्रीय संवाद और सहयोग के लिए एक प्रभावी भाषाई ढांचा प्रदान करती है।

278. (A) 'A' और 'R' दोनों सही हैं और 'R', 'A' की सही व्याख्या है।
संयुक्त राष्ट्र महासभा को 'विश्व की संसद' इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह एकमात्र ऐसा वैश्विक मंच है जहाँ दुनिया के सभी संप्रभु राष्ट्रों को अपनी आवाज उठाने का समान अवसर प्राप्त होता है। यहाँ 'एक देश, एक वोट' का सिद्धांत संप्रभु समानता के विचार को पूर्णतः चरितार्थ करता है, जो सुरक्षा परिषद की वीटो वाली व्यवस्था के विपरीत है। महासभा में होने वाली चर्चाएं अंतरराष्ट्रीय जनमत का प्रतिनिधित्व करती हैं और वैश्विक मानदंडों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यद्यपि इसके प्रस्ताव बाध्यकारी नहीं होते, परंतु इनकी नैतिक शक्ति और सार्वभौमिकता इसे वैश्विक लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण और अनिवार्य स्तंभ बनाती है। यह संगठन के भीतर लोकतांत्रिक समावेशिता और संप्रभु समानता के सिद्धांतों को सुदृढ़ करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। महासभा दुनिया के सभी राष्ट्रों को अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर खुलकर चर्चा करने के लिए एक अद्वितीय और सार्वभौमिक मंच प्रदान करती है, जहाँ प्रत्येक देश को अपनी बात रखने और वैश्विक एजेंडा को प्रभावित करने का समान अवसर मिलता है। यह अंतरराष्ट्रीय राजनीति और सुरक्षा प्रबंधन में एक निर्णायक और अपरिहार्य भूमिका निभाने वाली वैश्विक संस्था है, जो सामूहिक वैश्विक उत्तरदायित्वों को पूरा करने का प्रतीक है।

279. (A) नागरिकों की रक्षा करने की आवश्यकता।
संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिकों को अक्सर एक बड़ी दुविधा का सामना करना पड़ता है जब किसी देश के आंतरिक संघर्ष में नागरिक हिंसा का शिकार हो रहे होते हैं। अहस्तक्षेप का सिद्धांत उन्हें राज्य के मामलों में हस्तक्षेप करने से रोकता है, लेकिन "रक्षा करने की जिम्मेदारी" उन्हें मासूम लोगों की जान बचाने के लिए कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करती है। यदि वे मूकदर्शक बने रहते हैं, तो संगठन की मानवीय साख पर सवाल उठते हैं, और यदि वे बल प्रयोग करते हैं, तो संप्रभुता के उल्लंघन का आरोप लगता है। यह जटिलता शांति स्थापना अभियानों की प्रभावशीलता और उनके नैतिक आधार को निरंतर चुनौतीपूर्ण बनाए रखती है। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना के तीन मूल स्तंभों - मेजबान की सहमति, निष्पक्षता और आत्मरक्षा में बल प्रयोग - का पालन करते हुए नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना एक अत्यंत कठिन कूटनीतिक और सैन्य कार्य है। यह संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में स्थिरता बहाल करने और मानवीय संकटों को रोकने के प्रयासों में संप्रभुता और मानवता के बीच के निरंतर द्वंद्व को स्पष्ट रूप से उजागर करता है। शांति अभियानों की सफलता इन परस्पर विरोधी सिद्धांतों के बीच एक न्यायसंगत और प्रभावी संतुलन बनाने की संयुक्त राष्ट्र की क्षमता पर निर्भर करती है।

280. (A) शांतिपूर्ण साधनों के माध्यम से भारत के राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ना।
भारतीय कूटनीति का प्राथमिक उत्तरदायित्व विश्व पटल पर भारत के आर्थिक, सुरक्षा और राजनीतिक हितों को सुरक्षित और मजबूत करना है। यह कार्य बातचीत, संवाद

Downloaded from www.pdf.tube

271. (C) निर्भरता सिद्धांत
निर्भरता सिद्धांत अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को दो मुख्य श्रेणियों, 'केंद्र' और 'परिधि', में विभाजित करके देखता है। 'केंद्र' में विकसित और औद्योगिक राष्ट्र शामिल हैं जो वैश्विक संसाधनों और पूंजी पर नियंत्रण रखते हैं। 'परिधि' में वे विकासशील देश आते हैं जो कच्चे माल और सस्ते श्रम की आपूर्ति करते हैं और केंद्र पर निर्भर रहते हैं। यह सिद्धांत मानता है कि केंद्र का विकास परिधि के संसाधनों के निरंतर शोषण का परिणाम है। यह संरचनात्मक विश्लेषण वैश्विक स्तर पर धन और शक्ति के स्थाई और गहरे असंतुलन को समझने के लिए एक अनिवार्य आधार प्रदान करता है। यह वैश्विक पूंजीवाद के शोषणकारी स्वरूप का गहराई से विश्लेषण करता है और यह स्पष्ट करता है कि कैसे विकासशील देशों का आर्थिक पिछड़ापन अंतरराष्ट्रीय आर्थिक शासन के ढांचे में निहित है। निर्भरता सिद्धांत विकासशील राष्ट्रों की आर्थिक स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक आर्थिक संरचनाओं में मौलिक सुधार की वकालत करता है। यह अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंधों में समानता और न्याय की मांग करने वाला एक महत्वपूर्ण सैद्धांतिक दृष्टिकोण है जो वैश्विक दक्षिण के राष्ट्रों के आर्थिक संघर्षों को एक तार्किक और ऐतिहासिक संदर्भ प्रदान करता है।

272. (B) गुटनिरपेक्ष आंदोलन
नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था (NIEO) की औपचारिक मांग 1973 में अल्जीयर्स में आयोजित गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन के दौरान सबसे मुखर रूप से की गई थी। इस आंदोलन के सदस्य देशों ने एकजुट होकर यह घोषणा की कि मौजूदा वैश्विक आर्थिक ढांचा उनके विकास के विरुद्ध है। उन्होंने व्यापारिक नियमों में बदलाव, प्राकृतिक संसाधनों पर संप्रभुता और तकनीकी हस्तांतरण जैसे महत्वपूर्ण सुधारों का आह्वान किया। यह मांग वैश्विक दक्षिण की आर्थिक स्वायत्तता प्राप्त करने की दिशा में एक ऐतिहासिक और संगठित प्रयास था, जिसने अंतरराष्ट्रीय विकास वार्ताओं के एजेंडे को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। एनआईईओ का पूरा विचार ही वैश्विक आर्थिक शक्ति के पुनर्वितरण और निर्धन राष्ट्रों की संप्रभुता को बढ़ाने पर केंद्रित था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने विकासशील राष्ट्रों को अपनी संप्रभुता सुरक्षित रखने और महाशक्तियों के दबाव से बचने के लिए एक साझा मंच प्रदान किया। यह सामूहिक प्रयास अंतरराष्ट्रीय आर्थिक शासन में समानता और न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में विकासशील देशों की साझा आकांक्षाओं और उनके संगठित कूटनीतिक संघर्ष का प्रतीक है, जो आज भी वैश्विक आर्थिक संबंधों में अत्यंत प्रासंगिक बना हुआ है।

273. (D) नीतिगत सुधार पर आधारित सशर्त सहायता
दक्षिण-दक्षिण सहयोग की एक प्रमुख विशेषता यह है कि यह विकसित देशों द्वारा दी जाने वाली सहायता के विपरीत किसी भी प्रकार की कठोर शर्तों पर आधारित नहीं होता। यह सहयोग एकजुटता, संप्रभुता के सम्मान और पारस्परिक लाभ के सिद्धांतों पर टिका है। इसमें विकासशील देश एक-दूसरे की आंतरिक नीतियों में हस्तक्षेप किए बिना संसाधनों और अनुभवों को साझा करते हैं। "सशर्त सहायता" अक्सर उत्तर-दक्षिण संबंधों की विशेषता रही है, जहाँ विकासशील देशों को सहायता के बदले अपनी नीतियों को बदलने के लिए विवश किया जाता है। इसके विपरीत, दक्षिण-दक्षिण सहयोग बराबरी की साझेदारी और आपसी विश्वास को बढ़ावा देता है। यह सामूहिक आत्मनिर्भरता को सुदृढ़ करने और अंतरराष्ट्रीय वार्ताओं में विकासशील देशों की स्थिति को मजबूत करने पर केंद्रित है। यह सहयोग उत्तरी देशों पर उनकी ऐतिहासिक आर्थिक निर्भरता को कम करने में अत्यंत सहायक होता है। यह वैश्विक दक्षिण के सशक्तिकरण की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जो राष्ट्रों के बीच समानता और परस्पर सम्मान के सिद्धांतों पर आधारित है, जिससे वैश्विक विकास के लिए एक नई, न्यायपूर्ण और समावेशी दिशा प्राप्त होती है जो निर्धन राष्ट्रों की गरिमा और उनकी स्वायत्तता को प्राथमिकता देती है।

274. (B) डब्ल्यूटीओ (WTO)
विश्व व्यापार संगठन के विवाद निपटान निकाय को अक्सर अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रणाली का 'सर्वोच्च रत्न' कहा जाता है क्योंकि यह सदस्य देशों के बीच व्यापारिक विवादों को सुलझाने के लिए एक अत्यंत शक्तिशाली और कानूनी रूप से बाध्यकारी तंत्र प्रदान करता है। यह निकाय सुनिश्चित करता है कि सभी देश व्यापार समझौतों के नियमों का ईमानदारी से पालन करें। इसके फैसलों का उल्लंघन करने वाले देशों के विरुद्ध व्यापारिक जवाबी कार्रवाई की जा सकती है, जो इसे अंतरराष्ट्रीय कानून के क्षेत्र में एक अद्वितीय और प्रभावशाली संस्था बनाता है। यह तंत्र छोटे देशों को बड़े व्यापारिक राष्ट्रों के भेदभावपूर्ण व्यवहार से बचाने में सहायक सिद्ध होता है। विश्व व्यापार संगठन का यह विवाद निपटान तंत्र गेट प्रणाली की तुलना में बहुत अधिक सुव्यवस्थित और प्रभावी है, जो व्यापारिक अनिश्चितता को कम करके वैश्विक वाणिज्य के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करता है। यह बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली में विश्वास बनाए रखने और व्यापारिक विवादों के न्यायसंगत समाधान के लिए एक अनिवार्य कानूनी ढांचा प्रदान करता है। यह वैश्विक बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा और समानता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण संस्थागत उपलब्धि है जो अंतरराष्ट्रीय आर्थिक शासन को मजबूती प्रदान करती है।

275. (C) आसियान (ASEAN)
जोफ़ान (ZOPFAN) घोषणा 1971 में आसियान देशों द्वारा अपनाई गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य दक्षिण-पूर्व एशिया को बाहरी शक्तियों के हस्तक्षेप से मुक्त एक शांति, स्वतंत्रता और तटस्थता का क्षेत्र बनाना था। यह घोषणा शीत युद्ध के तनावों के बीच क्षेत्र की सुरक्षा और स्वायत्तता को सुरक्षित रखने का एक महत्वपूर्ण प्रयास थी। इसके माध्यम से आसियान सदस्यों ने सामूहिक रूप से यह संकल्प लिया कि वे किसी भी महाशक्ति के संघर्ष का हिस्सा नहीं बनेंगे। यह नीति आज भी क्षेत्र में क्षेत्रीय संप्रभुता बनाए रखने और बाहरी प्रभाव को संतुलित करने के लिए आसियान के रणनीतिक दृष्टिकोण की एक महत्वपूर्ण आधारशिला बनी हुई है। आसियान का यह तटस्थता का सिद्धांत क्षेत्रीय स्थिरता और परस्पर विश्वास को सुदृढ़ करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। यह एशियाई राष्ट्रों की अपनी सुरक्षा नियति खुद तय करने की दृढ़ इच्छाशक्ति

NODIA

व्यापक वैश्विक बहस शुरु की। यह संवाद वैश्विक आर्थिक असमानता को दूर करने और निर्धन राष्ट्रों को अंतरराष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली में सक्रिय और समान भागीदार बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण और निरंतर चलने वाली ऐतिहासिक प्रक्रिया की महत्ता को रेखांकित करता है।

285. (C) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य वास्तव में टैरिफ और कोटा जैसी व्यापारिक बाधाओं को कम करके अंतरराष्ट्रीय वाणिज्य को सुगम बनाना है। हालांकि, यह कहना गलत है कि वार्ताओं का दोहा दौर शीघ्र और सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इसके विपरीत, दोहा दौर 2001 में अपनी शुरुआत के बाद से ही विकसित और विकासशील देशों के बीच कृषि सब्सिडी और बाजार पहुंच जैसे जटिल मुद्दों पर गंभीर मतभेदों के कारण लंबे समय तक अधर में लटका रहा। यह वार्ताओं के इतिहास का सबसे लंबा और चुनौतीपूर्ण दौर बन गया है, जो वैश्विक व्यापार प्रणाली में सुधार की जटिलताओं और राष्ट्रों के बीच के गहरे हितों के टकराव को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। दोहा विकास दौर का मुख्य लक्ष्य वैश्विक व्यापार नियमों में सुधार करना और विशेष रूप से विकासशील देशों के लिए बेहतर अवसर पैदा करना था, परंतु विकसित राष्ट्रों की अनिच्छा ने इसे पंगु बना दिया। यह बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली में विश्वास बनाए रखने और न्यायसंगत व्यापार नियमों की दिशा में सुधार की राह में एक स्थाई और गंभीर चुनौती बनी हुई है, जो अंतरराष्ट्रीय आर्थिक शासन में समानता और समावेशिता सुनिश्चित करने की महत्ता को रेखांकित करती है।

286. (C) प्रत्यक्ष सैन्य अधिकार और प्रशासन
नव-उपनिवेशवाद की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें पुराने उपनिवेशवाद की तरह किसी देश पर प्रत्यक्ष सैन्य कब्जा या प्रशासनिक नियंत्रण नहीं किया जाता। इसके स्थान पर, शक्तिशाली राष्ट्र अपनी आर्थिक श्रेष्ठता, अंतरराष्ट्रीय ऋणों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से अन्य देशों की नीतियों को नियंत्रित करते हैं। वे सांस्कृतिक साम्राज्यवाद का उपयोग करके लोगों की सोच और जीवनशैली को प्रभावित करते हैं, जिससे बौद्धिक निर्भरता बढ़ती है। अतः, प्रत्यक्ष सैन्य अधिकार का अभाव ही इसे पारंपरिक उपनिवेशवाद से अलग और आधुनिक दुनिया के लिए अधिक सूक्ष्म एवं खतरनाक बनाता है, क्योंकि यह राष्ट्रों की वास्तविक संप्रभुता को चुपचाप खोखला कर देता है। नव-उपनिवेशवाद प्रत्यक्ष नियंत्रण के स्थान पर अप्रत्यक्ष माध्यमों से पूर्व उपनिवेशों का आर्थिक शोषण जारी रखने की एक सोची-समझी रणनीतिक पद्धति है। यह स्वतंत्र राष्ट्रों की आर्थिक संप्रभुता और उनके स्वावलंबन के संघर्ष को प्रतिबिंबित करता है। यह अवधारणा अंतरराष्ट्रीय संबंधों में आर्थिक और सांस्कृतिक शक्ति के अप्रत्यक्ष रूपों को समझने के लिए अनिवार्य है, जो वैश्विक स्तर पर संप्रभुता की वास्तविक सीमाओं और विकसित राष्ट्रों के निरंतर बने रहने वाले प्रभुत्व को गहराई से उजागर करती है।

287. (C) मैक्सिको
मैक्सिको ओपेक का सदस्य नहीं है, यद्यपि यह दुनिया के प्रमुख तेल उत्पादक देशों में से एक है। मैक्सिको ने हमेशा अपनी तेल नीति को स्वतंत्र रूप से संचालित करना पसंद किया है और ओपेक के उत्पादन कोटा के बंधनों में बंधने से इनकार किया है। हालांकि वह अक्सर ओपेक+ वार्ताओं में एक पर्यवेक्षक या सहयोगी के रूप में भाग लेता है, लेकिन वह संगठन का औपचारिक हिस्सा नहीं है। सऊदी अरब, वेनेजुएला और नाइजीरिया ओपेक के अत्यंत महत्वपूर्ण और स्थाई सदस्य हैं जो वैश्विक तेल कीमतों को प्रभावित करने के लिए संगठन की सामूहिक उत्पादन नीतियों का कड़ाई से पालन करते हैं और उसमें सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ओपेक की स्थापना पेट्रोलियम निर्यातक देशों के बीच नीतियों के समन्वय और सदस्य देशों के हितों की रक्षा के लिए की गई थी। संस्थापक राष्ट्रों ने अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार में अपनी संप्रभुता को पुनः स्थापित करने और विदेशी कंपनियों के प्रभुत्व को कम करने के लिए यह पहल की थी। यद्यपि मैक्सिको एक बड़ा उत्पादक है, परंतु इसकी आर्थिक और कूटनीतिक प्राथमिकताएं उसे ओपेक की औपचारिक सदस्यता से दूर रखती हैं, जो अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार में विभिन्न राष्ट्रों के अलग-अलग रणनीतिक दृष्टिकोणों को स्पष्ट रूप से उजागर करता है।

288. (A) वह सिद्धांत कि द्विपक्षीय और विवादास्पद मुद्दों पर चर्चा नहीं की जानी है।
सार्क की कार्यप्रणाली में सबसे बड़ी संरचनात्मक दुर्बलता इसके चार्टर का वह प्रावधान है जो सदस्य देशों को द्विपक्षीय विवादों को आधिकारिक बैठकों में उठाने से रोकता है। इसका उद्देश्य विवादों को टालना था, लेकिन व्यावहारिक रूप से इसने संगठन को पंगु बना दिया है क्योंकि दक्षिण एशिया की अधिकांश समस्याएं दो देशों के बीच के तनावों से ही जुड़ी हैं। जब तक मुख्य विवादों पर चर्चा नहीं होती, तब तक क्षेत्रीय सहयोग की बड़ी योजनाओं पर सहमति बनाना लगभग असंभव हो जाता है। यह "चर्चा न करने का सिद्धांत" सार्क की प्रभावशीलता में सबसे बड़ी रुकावट बन गया है, जो इसे केवल एक प्रतीकात्मक मंच तक सीमित कर देता है। दक्षिण एशियाई क्षेत्र के समग्र विकास और एकीकरण के लिए इन द्विपक्षीय मतभेदों को दूर करना और परस्पर विश्वास बहाल करना अनिवार्य है। राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी और आपसी अविश्वास ने सार्क की प्रभावशीलता और इसके विकास लक्ष्यों की प्राप्ति को अत्यंत सीमित कर दिया है। सार्क के भविष्य की प्रासंगिकता के लिए यह आवश्यक है कि सदस्य राष्ट्र द्विपक्षीय तनावों को क्षेत्रीय सहयोग के मार्ग में बाधा न बनने दें, जो दक्षिण एशिया के करोड़ों लोगों की समृद्धि और शांति के लिए निर्णायक है।

289. (A) महासभा और सुरक्षा परिषद।
अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) संयुक्त राष्ट्र का मुख्य न्यायिक अंग है जो न केवल राज्यों के बीच विवाद सुलझाता है, बल्कि कानूनी प्रश्नों पर अपनी विशेषज्ञ राय भी देता है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार, महासभा और सुरक्षा परिषद को यह विशेष अधिकार प्राप्त है कि वे किसी भी जटिल अंतरराष्ट्रीय कानूनी

Click Here to Buy book on Amazon

मुद्दे पर न्यायालय से परामर्शदात्री राय मांग सकें। यह राय कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होती, परंतु अंतरराष्ट्रीय कानून की व्याख्या करने में इसका अत्यंत उच्च नैतिक और कानूनी महत्व होता है। यह प्रक्रिया संयुक्त राष्ट्र के अन्य अंगों को जटिल विवादों और नीतिगत निर्णयों के दौरान सही कानूनी दिशा प्राप्त करने में एक अनिवार्य और विश्वसनीय मार्गदर्शन प्रदान करती है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड के 'द हेग' शहर में स्थित है, जहाँ से यह अंतरराष्ट्रीय न्याय और विवाद निपटान की अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाता है। यह अंतरराष्ट्रीय कानून के शासन को बनाए रखने और न्याय सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। परामर्शदात्री राय की यह व्यवस्था अंतरराष्ट्रीय संबंधों में शांतिपूर्ण संवाद और विधिक स्पष्टता को बढ़ावा देने का एक प्रभावी माध्यम है, जो वैश्विक शासन की स्थिरता और न्यायसंगत कार्यप्रणाली के लिए अनिवार्य है।

290. (A) P-2, Q-3, R-4, S-1
संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न अंग और उनके कार्य संगठन की समग्र प्रभावशीलता और वैश्विक शांति में उनके योगदान को परिभाषित करते हैं। सुरक्षा परिषद अपनी शक्तिशाली वीटो शक्ति के लिए जानी जाती है जो वैश्विक निर्णयों को प्रभावित करती है। शांति स्थापना अभियानों में शामिल सैनिकों को उनकी नीली टोपियों के कारण 'ब्लू हेलमेट' कहा जाता है। आर्थिक और सामाजिक परिषद का मुख्य कार्य अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक और आर्थिक विकास की गतिविधियों का समन्वय करना है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड के 'द हेग' शहर में स्थित है, जहाँ से यह अंतरराष्ट्रीय न्याय और विवाद निपटान की अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाता है। ये सभी अंग और उनकी विशिष्ट भूमिकाएं मिलकर एक सुव्यवस्थित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का निर्माण करते हैं। यह अंतरराष्ट्रीय कूटनीति और संयुक्त राष्ट्र के क्रमिक विकास का एक व्यवस्थित सारांश है। प्रत्येक अंग अपनी शक्तियों और उत्तरदायित्वों के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय शांति, विकास और न्याय को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। यह संगठन की संरचनात्मक मजबूती और उसके वैश्विक लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में एक अनिवार्य संस्थागत ढांचा प्रदान करता है, जो मानवता के सुरक्षित और न्यायपूर्ण भविष्य के लिए निर्णायक है।

291. (A) गठबंधन बनाना, प्रस्तावों पर बातचीत करना और राष्ट्रीय एवं समूह हितों के लिए संयुक्त राष्ट्र मंच का लाभ उठाना।
गुटनिरपेक्ष आंदोलन के गठन में भारत की भूमिका उसकी दूरदर्शी और साहसिक विदेश नीति का प्रमाण थी। शीत युद्ध के दौरान जब दुनिया दो विरोधी सैन्य गुटों में बंट रही थी, भारत ने नव स्वतंत्र राष्ट्रों को एक ऐसा मंच दिया जहाँ वे अपनी संप्रभुता बनाए रख सकें। यह पहल केवल महाशक्तियों से दूरी बनाने के लिए नहीं थी, बल्कि यह विकासशील देशों की सामूहिक आवाज को बुलंद करने और वैश्विक शांति के लिए एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करने का प्रयास था। इस आंदोलन ने भारत को वैश्विक दक्षिण के एक स्वाभाविक और नैतिक नेता के रूप में प्रतिष्ठित किया, जिसने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक संतुलनकारी शक्ति के रूप में कार्य किया। गुटनिरपेक्षता की नीति ने विकासशील राष्ट्रों को अपनी संप्रभुता सुरक्षित रखने और महाशक्तियों के दबाव से बचने के लिए एक साझा मंच प्रदान किया। यह आज भी भारत की विदेश नीति के नैतिक और व्यावहारिक आधार के रूप में अत्यंत प्रासंगिक है। भारत ने इस आंदोलन के माध्यम से उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का पुरजोर विरोध किया और एक न्यायपूर्ण विश्व व्यवस्था के निर्माण पर बल दिया। यह भारत की रणनीतिक स्वायत्तता और वैश्विक शांति के प्रति उसकी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करने वाला एक आधारभूत सिद्धांत है।

NODIA

292. (A) अफगानिस्तान में अस्थिरता और इसके क्षेत्रीय निहितार्थ।
अफगानिस्तान में बनी रहने वाली राजनीतिक अस्थिरता और चरमपंथ भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक अत्यंत गंभीर और प्रत्यक्ष चिंता का विषय है। वहां की स्थितियों का असर पूरे दक्षिण एशियाई क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था पर पड़ता है, जिससे आतंकवाद और शरणार्थी संकट जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। भारत ने हमेशा एक स्थिर, लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण अफगानिस्तान का समर्थन किया है क्योंकि वहां की शांति भारत के अपने सुरक्षा हितों के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। पड़ोस में किसी भी प्रकार का राजनीतिक शून्य या कट्टरपंथ का उदय भारत की आंतरिक सुरक्षा और क्षेत्रीय रणनीतिक संतुलन के लिए एक बड़ी चुनौती और निरंतर बनी रहने वाली सुरक्षा चिंता है। अफगानिस्तान की स्थिरता न केवल द्विपक्षीय संबंधों के लिए, बल्कि भारत की 'पड़ोसी पहले' नीति और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी परियोजनाओं की सफलता के लिए भी अनिवार्य है। वहां की मानवीय स्थिति और सुरक्षा वातावरण भारत की क्षेत्रीय कूटनीति में एक संवेदनशील और महत्वपूर्ण प्राथमिकता बनी हुई है। भारत अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर अफगानिस्तान में शांति बहाली और मानवीय सहायता प्रदान करने की दिशा में सक्रिय प्रयास करता है, जो क्षेत्रीय अखंडता और सुरक्षा के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

293. (B) दस्तावेजों को मोड़ने की प्रक्रिया।
'कूटनीति' या 'डिप्लोमेसी' शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द 'डिप्लोमा' से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है "दो परतों में मोड़ा गया कागज"। प्राचीन काल में, राजाओं द्वारा भेजे जाने वाले आधिकारिक दस्तावेजों और संधियों को इस प्रकार मोड़ा और सीलबंद किया जाता था कि उन्हें केवल संबंधित व्यक्ति ही पढ़ सके। समय के साथ, इन महत्वपूर्ण दस्तावेजों को प्रबंधित करने और उनके माध्यम से बातचीत करने की कला ही कूटनीति कहलाई। आज यह शब्द अंतरराष्ट्रीय संबंधों के संचालन, वार्ताओं और प्रतिनिधित्व की उस सूक्ष्म प्रक्रिया को संदर्भित करता है जो राष्ट्रों के बीच शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित संवाद सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत अनिवार्य और महत्वपूर्ण साधन बन गई है। कूटनीति किसी राष्ट्र की विदेश नीति के लक्ष्यों को धरातल पर उतारने की कला है। इसके माध्यम से एक देश अन्य राष्ट्रों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ निरंतर संवाद और बातचीत करके अपने हितों की रक्षा करता है। कूटनीति का मुख्य कार्य विवादों को सुलझाना, गठबंधन बनाना और आपसी सहयोग के नए अवसर खोजना है। यह एक शांतिपूर्ण उपकरण है जो अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में स्थिरता और समझ विकसित

करने में सहायक होता है। एक सफल कूटनीति राष्ट्र की प्रतिष्ठा और उसके वैश्विक प्रभाव को सुदृढ़ करती है, जो राष्ट्रों के बीच टकराव को कम करने का एक अनिवार्य माध्यम है।

294. (B) मुद्दा-आधारित सहभागिता पर आधारित एक बहु-पक्षीय (multi-aligned) दृष्टिकोण।
आधुनिक भारतीय विदेश नीति गुटनिरपेक्षता के अपने पारंपरिक स्वरूप से आगे बढ़कर अब एक अधिक गतिशील और लचीले दृष्टिकोण की ओर बढ़ गई है जिसे अक्सर 'बहु-पक्षीय' कहा जाता है। इसका अर्थ है कि भारत अब किसी एक शक्ति गुट से स्थाई रूप से जुड़े बिना विभिन्न वैश्विक शक्तियों के साथ विशिष्ट मुद्दों पर आधारित साझेदारी करता है। यह दृष्टिकोण भारत को अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों के साथ अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार स्वतंत्र रूप से जुड़ने की सुविधा प्रदान करता है। यह बदलाव भारत की बढ़ती आर्थिक और सामरिक शक्ति के साथ-साथ एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में अपनी भूमिका को अधिक प्रभावी और परिणाम-उन्मुख बनाने की उसकी रणनीतिक परिपक्वता को दर्शाता है। "रणनीतिक स्वायत्तता" आज भारत की विदेश नीति की एक प्रमुख विशेषता है, जो उसे अंतरराष्ट्रीय मंच पर एक स्वतंत्र और प्रभावशाली खिलाड़ी के रूप में स्थापित करती है। यह दृष्टिकोण भारत को अपनी सुरक्षा और आर्थिक नीतियों को किसी बाहरी दबाव के अधीन होने से बचाने में सक्षम बनाता है। बहु-पक्षीय जुड़ाव आज की जटिल वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए भारत को अधिक रणनीतिक लचीलापन और अंतरराष्ट्रीय संबंधों में एक संतुलनकारी शक्ति के रूप में कार्य करने की क्षमता प्रदान करता है, जो राष्ट्रहितों की प्रभावी प्राप्ति हेतु अनिवार्य है।

295. (C) केवल 1 और 3
संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने की प्राथमिक जिम्मेदारी सुरक्षा परिषद को दी गई है। इसके अतिरिक्त, चार्टर में किसी भी प्रकार के संशोधन के लिए परिषद के सभी पांच स्थाई सदस्यों की लिखित सहमति और उनकी वीटो शक्ति का समर्थन अनिवार्य है। हालांकि, यह धारणा गलत है कि संयुक्त राष्ट्र के पास कोई अपनी स्थाई सेना है; यह पूरी तरह से सदस्य देशों द्वारा स्वैच्छिक आधार पर प्रदान किए गए सैनिकों पर निर्भर है। ये प्रावधान सुरक्षा परिषद के पांच स्थाई सदस्यों के असाधारण और निर्णायक प्रभाव को स्पष्ट रूप से रेखांकित करते हैं, जो संगठन की निर्णय लेने की प्रक्रिया और इसकी पूरी संरचना की आधारशिला बने हुए हैं। सुरक्षा परिषद की यह विशेष शक्ति और जिम्मेदारी अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और संघर्ष प्रबंधन की संरचना में महाशक्तियों की विशिष्ट भूमिका को स्पष्ट करती है। सुधार के बिना संयुक्त राष्ट्र की लोकतांत्रिक वैधता और उसकी प्रवर्तन क्षमता को सुदृढ़ करना संभव नहीं है, जो वैश्विक न्याय की दिशा में एक निरंतर बनी रहने वाली चुनौती है। यह संगठन की उन प्रवर्तन शक्तियों का केंद्र है जो इसे अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में आक्रामकता को रोकने और शांति बनाए रखने का एक प्रभावी माध्यम बनाती हैं, जो वैश्विक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए अपरिहार्य है।

296. (B) केंद्र द्वारा सक्रिय रूप से निर्मित और बनाए रखी गई स्थिति।
निर्भरता सिद्धांतकारों का तर्क है कि विकासशील देशों का अल्पविकास कोई प्राकृतिक घटना या आकस्मिक चरण नहीं है। इसके बजाय, यह विकसित राष्ट्रों (केंद्र) द्वारा अपनी समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए जानबूझकर बनाई गई एक व्यवस्था है। केंद्र के देश वैश्विक व्यापार नियमों, कर्ज और तकनीकी एकाधिकार का उपयोग इस प्रकार करते हैं कि परिधि के देश हमेशा कच्चे माल के निर्यातक और सस्ते श्रम के स्रोत बने रहें। यह संरचनात्मक असमानता विकासशील देशों को एक ऐसे चक्र में बांधे रखती है जहाँ उनकी आर्थिक प्रगति हमेशा विकसित राष्ट्रों के लाभ के अधीन होती है। यह सिद्धांत वैश्विक गरीबी को शोषणकारी अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संरचनाओं के सीधे परिणाम के रूप में देखता है। निर्भरता सिद्धांत अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंधों के भीतर मौजूद संरचनात्मक बाधाओं और विकसित राष्ट्रों के अप्रत्यक्ष प्रभुत्व का गहराई से विश्लेषण करने वाला एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है। यह वैश्विक स्तर पर धन और शक्ति के असमान वितरण के ऐतिहासिक और वर्तमान कारणों को समझने के लिए अनिवार्य है। विकासशील राष्ट्रों की आर्थिक स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए यह सिद्धांत वैश्विक आर्थिक शासन के ढांचे में मौलिक सुधार की वकालत करता है, जो अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंधों में समानता और न्याय की मांग करने वाला एक महत्वपूर्ण सैद्धांतिक और रणनीतिक आधार है।

297. (B) प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाएं।
जी-20 समूह की महत्ता और इसकी व्यापक प्रतिनिधित्व क्षमता का मुख्य कारण इसमें भारत, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसी प्रमुख उभरती हुई शक्तियों का शामिल होना है। जी-7 के विपरीत, जिसमें केवल धनी औद्योगिक राष्ट्र हैं, जी-20 में दुनिया के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों और अलग-अलग विकास स्तरों वाली अर्थव्यवस्थाएं एक साथ बैठती हैं। यह विविधता जी-20 को वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक अधिक वैध और समावेशी मंच प्रदान करती है। इसमें शामिल देश सामूहिक रूप से दुनिया की अधिकांश जीडीपी और जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिससे उनके द्वारा लिए गए निर्णय पूरी दुनिया के लिए अधिक प्रभावी और स्वीकार्य बन जाते हैं। वर्तमान वैश्विक आर्थिक शासन में जी-20 की भूमिका अपरिहार्य हो गई है, क्योंकि यह विकसित और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाकर वैश्विक चुनौतियों का सामूहिक समाधान खोजने के लिए एक प्रभावी मंच प्रदान करता है। यह वैश्विक सहयोग के बदलते स्वरूप का एक आदर्श उदाहरण है जहाँ विकासशील राष्ट्रों की भूमिका अब वैश्विक शासन में अनिवार्य और अत्यंत निर्णायक हो गई है। जी-20 की समावेशी प्रकृति इसे वैश्विक वित्तीय चुनौतियों का सामना करने के लिए अधिक वैध और प्रभावी मंच बनाती है, जो अंतरराष्ट्रीय आर्थिक नीतियों के निर्धारण में समानता और न्याय सुनिश्चित करती है।

298. (A) 'A' और 'R' दोनों सही हैं और 'R', 'A' की सही व्याख्या है।
भारत ने लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की वकालत की है क्योंकि उसे लगता है कि परिषद की वर्तमान

Downloaded from www.pdf.tube

(B) राज्य न्यायपालिका
(C) केंद्रीय मंत्रिमंडल
(D) नीति आयोग

78. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के त्यागपत्र से स्वतः ही किसका त्यागपत्र हो जाता है?
(A) विधानसभा अध्यक्ष का
(B) राज्यपाल का
(C) संपूर्ण मंत्रिपरिषद का
(D) महाधिवक्ता का

79. विधानसभा में विपक्ष की प्राथमिक भूमिका क्या है?
(A) रचनात्मक आलोचना करना और सरकार को जवाबदेह ठहराना।
(B) सरकार के सभी कार्यों में बाधा डालना।
(C) एक समानांतर सरकार बनाना।
(D) विधानसभा के सभी सत्रों का बहिष्कार करना।

80. भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करें:
1. भारत के राष्ट्रपति निष्कासन का आदेश जारी करते हैं।
2. संसद के प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जाता है।
3. आरोपों की जांच के लिए एक जांच समिति का गठन किया जाता है।
4. निष्कासन प्रस्ताव पर 100 सदस्यों (लोकसभा) या 50 सदस्यों (राज्यसभा) द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं और इसे अध्यक्ष को सौंपा जाता है।

(A) 4, 3, 2, 1
(B) 3, 4, 2, 1
(C) 4, 2, 3, 1
(D) 2, 3, 4, 1

81. मध्य प्रदेश के मुख्य राजनीतिक दलों में से एक, भारतीय जनता पार्टी, आम तौर पर किस विचारधारा के साथ पहचानी जाती है?
(A) साम्यवाद
(B) राष्ट्रवाद और रूढ़िवाद
(C) लोकतांत्रिक समाजवाद
(D) उदारवाद

82. 2000 में अपने विभाजन से पहले, मध्य प्रदेश किस मामले में भारत का सबसे बड़ा राज्य था?
(A) क्षेत्रफल
(B) जनसंख्या
(C) जिलों की संख्या
(D) सकल घरेलू उत्पाद

83. मध्य प्रदेश विधानसभा को आहूत करने और सत्रावसान करने की शक्ति किसके पास है?
(A) मुख्यमंत्री
(B) विधानसभा अध्यक्ष
(C) राज्यपाल
(D) भारत के राष्ट्रपति

84. मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या किसके द्वारा निर्धारित की जाती है?
(A) राज्यपाल
(B) मुख्यमंत्री
(C) विधानसभा
(D) भारत का संविधान

85. निम्नलिखित में से कौन सा साधन मध्य प्रदेश विधानसभा में कार्यपालिका को नियंत्रित करने के लिए विपक्ष द्वारा उपयोग नहीं किया जाता है?
(A) प्रश्नकाल
(B) अध्यादेश प्रख्यापित करना
(C) स्थगन प्रस्ताव
(D) अविश्वास प्रस्ताव

NODIA

86. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ स्थित है?
(A) भोपाल
(B) इंदौर
(C) जबलपुर
(D) ग्वालियर

87. मध्य प्रदेश की चुनावी राजनीति में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक कौन सा है?
(A) राष्ट्रीय राजधानी से निकटता।
(B) राज्य स्तर के नेताओं का करिश्मा और आकर्षण।
(C) अंतर्राष्ट्रीय खेलों में राज्य का प्रदर्शन।
(D) राज्य की विदेश नीति की पहल।

88. 1956 का राज्यों का पुनर्गठन इस विचार पर आधारित था कि प्रशासनिक इकाइयों को किनके अनुरूप होना चाहिए?
(A) प्रमुख भाषाई समूह
(B) आर्थिक क्षेत्र
(C) सैन्य कमान संरचनाएं
(D) ऐतिहासिक साम्राज्य

89. 2000 में मध्य प्रदेश के विभाजन के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए:
1. इससे झारखंड राज्य का गठन हुआ।
2. इसका प्राथमिक औचित्य प्रशासनिक सुविधा और केंद्रित विकास था।
3. नए राज्य छत्तीसगढ़ ने मध्य प्रदेश की आदिवासी जनसंख्या और खनिज संपदा का एक बड़ा हिस्सा ले लिया।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 3

अध्याय 09
मध्य प्रदेश की राजनीति

1. 1956 में राज्यों के पुनर्गठन का प्राथमिक आधार क्या था, जिसके परिणामस्वरूप मध्य प्रदेश का गठन हुआ?
(A) प्रशासनिक सुविधा
(B) भाषाई समरूपता
(C) आर्थिक व्यवहार्यता
(D) भौगोलिक निरंतरता

2. कौन सा कथन मध्य प्रदेश के राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति का सही वर्णन करता है?
(A) राज्यपाल राज्य का नाममात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है।
(B) राज्यपाल राज्य का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है।
(C) राज्यपाल केवल केंद्र सरकार का एक प्रतिनिधि होता है।
(D) राज्यपाल सीधे राज्य की जनता द्वारा चुना जाता है।

3. मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष का मुख्य कार्य क्या है?
(A) सत्ताधारी दल के नेता के रूप में कार्य करना।
(B) राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना।
(C) विधानसभा के सत्रों की अध्यक्षता करना और व्यवस्था बनाए रखना।
(D) विधानसभा द्वारा पारित कानूनों पर न्यायिक पुनरावलोकन करना।

4. मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने का मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र किस श्रेणी में आता है?
(A) अपीलीय क्षेत्राधिकार
(B) सलाहकार क्षेत्राधिकार
(C) पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार
(D) मूल क्षेत्राधिकार

5. निम्नलिखित प्रश्न में, अभिकथन (A) के बाद कारण (R) दिया गया है। सही विकल्प चुनें:
अभिकथन (A): मध्य प्रदेश में दलीय व्यवस्था मुख्य रूप से दो प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच द्विध्रुवीय प्रतिस्पर्धा द्वारा पहचानी जाती है।
कारण (R): कई क्षेत्रीय और छोटे दलों की उपस्थिति के कारण राज्य में लगातार त्रिशंकु विधानसभाएं बनी हैं।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

6. 2000 में मध्य प्रदेश का विभाजन मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस मुद्दे के समाधान की आवश्यकता से प्रेरित था?
(A) निरंतर भाषाई संघर्ष और पृथक राज्य की मांग।
(B) क्षेत्रीय असमानताएं और छत्तीसगढ़ क्षेत्र का विकास।
(C) अंतर्राष्ट्रीय सीमा विवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताएं।
(D) छोटे राज्यों के निर्माण के संबंध में एक संवैधानिक जनादेश।

7. निम्नलिखित में से कौन सी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की शक्ति नहीं है?
(A) अन्य मंत्रियों की नियुक्ति पर राज्यपाल को सलाह देना।
(B) मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करना।
(C) मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों की सूचना राज्यपाल को देना।
(D) मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना।

8. मध्य प्रदेश के गठन के संबंध में सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
सूची I: (पूर्व क्षेत्र)
P. मध्य प्रांत एवं बरार
Q. विंध्य प्रदेश
R. भोपाल
S. सिरोंज उपखंड
सूची II: (स्थिति/उत्पत्ति)
1. एक भाग C राज्य जिसका पूर्णतः विलय कर दिया गया
2. एक रियासत जो भाग C राज्य बनी
3. 1956 में नए राज्य का एक प्रमुख हिस्सा
4. राजस्थान का एक क्षेत्र जिसे मध्य प्रदेश में जोड़ा गया
(A) P-3, Q-1, R-2, S-4
(B) P-1, Q-2, R-3, S-4
(C) P-4, Q-3, R-1, S-2
(D) P-2, Q-4, R-3, S-1

9. मध्य प्रदेश में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किस निकाय के प्रति उत्तरदायी है?
(A) राज्यपाल
(B) मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय

Click Here to Buy book on Amazon

54. यदि मध्य प्रदेश में सत्तारूढ़ दल विधानसभा में अपना बहुमत खो देता है, तो मुख्यमंत्री का संवैधानिक दायित्व क्या है?
(A) राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करना।
(B) राज्यपाल से उन्हें पद पर बने रहने देने का अनुरोध करना।
(C) जनमत संग्रह की मांग करना।
(D) अपने पद से त्यागपत्र देना।

55. निम्नलिखित प्रश्न में, अभिकथन (A) के बाद कारण (R) दिया गया है। सही विकल्प चुनें:
अभिकथन (A): मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष से सदन की कार्यवाही के संचालन में निष्पक्ष रहने की अपेक्षा की जाती है।
कारण (R): अध्यक्ष चुने जाने पर, उनके लिए विधि सम्मत रूप से अपने राजनीतिक दल से त्यागपत्र देना अनिवार्य है।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

56. निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मध्य प्रदेश मंत्रिपरिषद का नहीं है?
(A) राज्य सरकार की नीतियों को तैयार करना।
(B) भारत के संविधान में संशोधन करना।
(C) वार्षिक राज्य बजट तैयार करना और प्रस्तुत करना।
(D) प्रशासनिक मामलों पर राज्यपाल को सलाह देना।

57. लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है कि:
(A) सरकार अपने पूरे कार्यकाल के लिए सत्ता में बनी रहे।
(B) सरकार के निर्णयों पर कभी प्रश्न न उठाए जाएं।
(C) न्यायपालिका विधायिका के अधीन बनी रहे।
(D) विधायिका के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित हो।

58. किसी अधीनस्थ न्यायालय से किसी मामले को अपने पास स्थानांतरित करने की मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है?
(A) मूल क्षेत्राधिकार
(B) पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार
(C) अपीलीय क्षेत्राधिकार
(D) सलाहकार क्षेत्राधिकार

59. 2000 में मध्य प्रदेश के विभाजन के परिणामस्वरूप मूल राज्य ने अपने किस महत्वपूर्ण हिस्से को खो दिया?
(A) वन आवरण और खनिज संसाधन।
(B) औद्योगिक और विनिर्माण आधार।
(C) प्रमुख महानगरीय शहर।
(D) कृषि मैदान।

60. सूची I (मध्य प्रदेश में संवैधानिक निकाय/पद) को सूची II (नियुक्ति प्राधिकारी) से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
सूची I:
P. राज्यपाल
Q. मुख्यमंत्री
R. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश
S. महाधिवक्ता
सूची II:
1. राज्यपाल
2. राष्ट्रपति
(A) P-2, Q-1, R-2, S-1
(B) P-1, Q-1, R-2, S-2
(C) P-2, Q-1, R-1, S-2
(D) P-1, Q-2, R-2, S-1

NODIA

61. मध्य प्रदेश की राजनीति में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख निर्धारक है?
(A) प्रवासी जनसंख्या के बीच जातीय संघर्ष।
(B) जातिगत समीकरणों और क्षेत्रीय पहचानों (जैसे मालवा, बघेलखंड) का प्रभाव।
(C) कृषि और औद्योगिक गुटों के बीच की गतिशीलता।
(D) कई सक्रिय सशस्त्र विद्रोही समूहों की उपस्थिति।

62. मध्य प्रदेश में राज्यपाल के अभिभाषण के संबंध में नीचे दो कथन दिए गए हैं:
कथन I: प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में मध्य प्रदेश विधानसभा में राज्यपाल का अभिभाषण सरकार की नीतियों की रूपरेखा प्रस्तुत करता है।
कथन II: राज्यपाल का अभिभाषण मंत्रिपरिषद से स्वतंत्र होकर राज्यपाल के कार्यालय द्वारा तैयार किया जाता है।
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
(D) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।

63. मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद का आकार किससे अधिक नहीं हो सकता?
(A) विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 10 प्रतिशत।
(B) विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15 प्रतिशत।
(C) विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 20 प्रतिशत।
(D) 50 मंत्रियों की एक निश्चित संख्या।

64. मध्य प्रदेश विधानसभा की एक प्राथमिक विधायी शक्ति है:
(A) वार्षिक राज्य बजट को अधिनियमित करना।
(B) युद्ध और शांति की घोषणा करना।
(C) अंतर्राष्ट्रीय संधियों की पुष्टि करना।
(D) राजदूतों की नियुक्ति करना।

65. बहुमत सिद्ध करने के लिए 'शक्ति परीक्षण' के दौरान अध्यक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण होती है क्योंकि वे:

(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

21. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद का कार्यकाल कितना होता है?
(A) नियुक्ति की तिथि से पांच वर्ष का निश्चित कार्यकाल।
(B) सरकार गठन की तिथि से छह वर्ष।
(C) विधानसभा के कार्यकाल के साथ, जब तक उसे सदन के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो।
(D) राज्यपाल के प्रसादपर्यंत एक अनिश्चित कार्यकाल।

22. मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष को किसके द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा पद से हटाया जा सकता है?
(A) मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा।
(B) विधानसभा द्वारा उसके सदस्यों के प्रभावी बहुमत से।
(C) दुर्व्यवहार के आधार पर उच्च न्यायालय द्वारा।
(D) भारत के राष्ट्रपति द्वारा।

23. 1956 के बाद मध्य प्रदेश की राजव्यवस्था की परिभाषित विशेषताओं में से एक थी:
(A) लगातार छोटा भौगोलिक आकार।
(B) समरूप भाषाई और सांस्कृतिक जनसंख्या।
(C) 1971 तक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा।
(D) विशाल आकार और महत्वपूर्ण क्षेत्रीय विविधता।

24. निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश के राज्यपाल की विधायी शक्ति का उदाहरण है?
(A) विधानसभा के सत्रों को आहूत करना और सत्रावसान करना।
(B) राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करना।
(C) आपराधिक सजा को क्षमा करना।
(D) मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करना।

25. मध्य प्रदेश की चुनावी राजनीति अक्सर किनके बीच मुकाबला दर्शाती है?
(A) कई मजबूत क्षेत्रीय दलों के बीच।
(B) एक राष्ट्रीय दल और कई क्षेत्रीय दलों के बीच।
(C) दो प्रमुख राष्ट्रीय दलों के बीच।
(D) चुनावी परिदृश्य पर हावी निर्दलीय उम्मीदवारों के बीच।

26. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
(A) यह मध्य प्रदेश राज्य के भीतर सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण है।
(B) इसकी स्थापना 2000 में राज्य के विभाजन के बाद की गई थी।
(C) इसके निर्णय भारत के अन्य सभी उच्च न्यायालयों पर बाध्यकारी हैं।
(D) इसके सभी न्यायाधीशों का स्थानांतरण अन्य राज्यों से किया जाता है।

27. मंत्रिपरिषद के 'सामूहिक उत्तरदायित्व' के सिद्धांत का अर्थ है कि:
(A) प्रत्येक मंत्री केवल अपने विशिष्ट विभाग के लिए उत्तरदायी है।
(B) सभी मंत्री व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री के प्रति उत्तरदायी हैं।
(C) मंत्री सामूहिक रूप से राज्य के राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी हैं।
(D) संपूर्ण मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है।

28. मध्य प्रदेश विधानसभा की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए:
1. इसके पास विधान परिषद बनाने या समाप्त करने की शक्ति है।
2. इसके पास राज्य सूची के विषयों पर अनन्य शक्ति है।
3. यह भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) केवल 2
(B) केवल 1 और 2
(C) केवल 2 और 3
(D) 1, 2 और 3

NODIA

29. 1956 में मध्य प्रदेश के गठन में पूर्व राज्यों मध्य प्रांत एवं बरार, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और किस क्षेत्र का एकीकरण किया गया था?
(A) कच्छ
(B) सौराष्ट्र
(C) भोपाल
(D) अजमेर

30. मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता की भूमिका महत्वपूर्ण है क्योंकि वे:
(A) इच्छानुसार सरकार को बर्खास्त कर सकते हैं।
(B) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में विधानसभा सत्रों की अध्यक्षता करते हैं।
(C) स्वतः ही अगले मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त हो जाते हैं।
(D) कैबिनेट मंत्री का दर्जा रखते हैं और सरकार की शक्ति पर नियंत्रण रखते हैं।

31. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को पद की शपथ कौन दिलाता है?
(A) मध्य प्रदेश के राज्यपाल
(B) भारत के राष्ट्रपति
(C) मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
(D) विधानसभा के अध्यक्ष

संरचना आज की बदलती भू-राजनीतिक वास्तविकताओं के अनुरूप नहीं है। परिषद का स्थाई ढांचा अभी भी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की पुरानी व्यवस्था पर आधारित है, जो भारत जैसे उभरते हुए बड़े लोकतंत्रों और अफ्रीका एवं लैटिन अमेरिका के प्रतिनिधित्व को पूरी तरह नकारता है। भारत का तर्क है कि जब तक सुरक्षा परिषद अधिक समावेशी और लोकतांत्रिक नहीं होगी, तब तक वह 21वीं सदी की जटिल सुरक्षा चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान नहीं कर पाएगी। परिषद के विस्तार की मांग वैश्विक शासन में न्याय और समानता स्थापित करने के भारत के व्यापक कूटनीतिक लक्ष्यों का हिस्सा है। सुरक्षा परिषद में सुधार के बिना संयुक्त राष्ट्र की लोकतांत्रिक वैधता और उसकी वैश्विक स्वीकार्यता को सुदृढ़ करना संभव नहीं है। यह अंतरराष्ट्रीय शासन प्रणाली में समानता और समावेशिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक अनिवार्य द्वंद्व है। सुधार के लिए जी-4 राष्ट्रों के सामूहिक प्रयास सुरक्षा परिषद को अधिक प्रतिनिधि और प्रभावी बनाने की दिशा में भारत की अडिग प्रतिबद्धता और रणनीतिक कूटनीति का प्रमाण हैं, जो वर्तमान बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की अनिवार्य और महत्वपूर्ण मांग है।

299. (C) सीमा विवाद और सीमा पार आतंकवाद।

पंचशील का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ एक-दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना है, लेकिन व्यवहार में इसे सबसे अधिक चुनौती सीमा विवादों और आतंकवाद से मिलती है। जब कोई देश दूसरे की सीमाओं का उल्लंघन करता है या अपनी धरती से आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देता है, तो वह सीधे तौर पर पंचशील की मूल भावना पर हमला करता है। ये मुद्दे राष्ट्रों के बीच गहरे अविश्वास को जन्म देते हैं और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा बनते हैं। भारत के संदर्भ में, पड़ोसी देशों के साथ अनसुलझे सीमा विवाद और प्रायोजित आतंकवाद ने अक्सर इन सिद्धांतों की प्रभावशीलता पर प्रश्नचिह्न लगाए हैं और द्विपक्षीय संबंधों को निरंतर तनावपूर्ण बनाए रखा है। ये चुनौतियां राष्ट्रों के बीच विश्वास की कमी को दूर करने और क्षेत्रीय शांति का वातावरण तैयार करने में बाधक हैं। पंचशील के सिद्धांत आज भी भारत की विदेश नीति के नैतिक आधार बने हुए हैं और वैश्विक स्तर पर संप्रभु समानता और न्यायसंगत अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की वकालत करते हैं। इन सिद्धांतों की सफलता राष्ट्रों की अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति परस्पर सम्मान सुनिश्चित करने की सामूहिक प्रतिबद्धता पर निर्भर करती है, जो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए अनिवार्य है।

300. (B) एक अधिक सक्रिय, परियोजना-आधारित और परिणाम-उन्मुख जुड़ाव।

'लुक ईस्ट' से 'एक्ट ईस्ट' की ओर भारत का बदलाव उसकी विदेश नीति में एक अधिक ऊर्जावान और ठोस दृष्टिकोण का प्रतीक है। जहाँ पुरानी नीति मुख्य रूप से आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को बेहतर बनाने तक सीमित थी, वहीं 'एक्ट ईस्ट' का जोर अब बुनियादी ढांचे, सुरक्षा सहयोग और कनेक्टिविटी परियोजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन पर है। इसमें दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ-साथ जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसी प्रमुख शक्तियों के साथ भी रणनीतिक संबंधों को सुदृढ़ करना शामिल है। यह नीति भारत की क्षेत्रीय प्रतिबद्धता को केवल शब्दों तक सीमित न रखकर उसे धरातल पर वास्तविक परिणामों में बदलने की इच्छाशक्ति को दर्शाती है, जिससे भारत इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में एक निर्णायक और प्रभावी शक्ति के रूप में उभर सके। यह नीति की गतिशीलता और बदलती वैश्विक परिस्थितियों के अनुरूप भारत की कूटनीतिक और आर्थिक दिशा को नया विस्तार प्रदान करने का एक सफल प्रयास है। क्षेत्रीय एकीकरण और सुरक्षा सहयोग के प्रति भारत की यह सक्रियता वर्तमान बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में अत्यंत आवश्यक है। 'एक्ट ईस्ट' नीति दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्रों के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी को नया आयाम प्रदान करती है, जो क्षेत्रीय स्थिरता और आर्थिक समृद्धि सुनिश्चित करने की दिशा में भारत की बढ़ती भूमिका और जिम्मेदारी को स्पष्ट रूप से उजागर करती है।

www.nodia.in

Downloaded from www.pdf.tube

(D) संसद की मंजूरी के बिना भारत के संविधान में संशोधन करना।

43. 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के संबंध में नीचे दो कथन दिए गए हैं:
कथन I: 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम ने 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए।
कथन II: 1956 के पुनर्गठन के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश सबसे बड़ा राज्य था।
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
(D) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।

44. अक्सर "भारत का हृदय" कहे जाने वाले मध्य प्रदेश राज्य की एक प्रमुख विशेषता क्या है?
(A) लंबी तटरेखा के साथ प्रायद्वीपीय स्थिति।
(B) हिमालयी स्थलाकृति।
(C) मरुस्थल जैसी शुष्क जलवायु।
(D) बिना किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा या तटरेखा के केंद्रीय स्थिति।

45. मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है।
2. विपक्ष का नेता उस समिति का हिस्सा होता है जो लोकायुक्त का चयन करती है।
3. इसके पास राज्य के बजट को पेश होने से रोकने का अधिकार है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) केवल 1
(B) केवल 1 और 2
(C) केवल 2 और 3
(D) 1, 2 और 3

46. मध्य प्रदेश के राज्यपाल निम्नलिखित में से किस स्थिति में अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते हैं?
(A) धन विधेयक को सहमति प्रदान करना।
(B) बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करना।
(C) किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना।
(D) राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करना।

47. मध्य प्रदेश में मंत्रिपरिषद के संगठन और संरचना का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है?
(A) राज्यपाल के परामर्श से मुख्यमंत्री द्वारा।
(B) विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा।
(C) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा।
(D) भारत के राष्ट्रपति द्वारा।

48. मध्य प्रदेश विधानसभा में कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय करने की शक्ति किसके पास है?
(A) वित्त मंत्री
(B) मुख्यमंत्री
(C) राज्यपाल
(D) विधानसभा अध्यक्ष

49. 2000 में मध्य प्रदेश से अलग छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण का एक मुख्य कारण क्या था?
(A) क्षेत्रीय जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली एक अलग बहुसंख्यक भाषा।
(B) बड़े राज्य के भीतर कथित उपेक्षा और कम विकास।
(C) स्वदेशी जनजातियों के संरक्षण के संबंध में संयुक्त राष्ट्र का एक प्रस्ताव।
(D) विशिष्ट क्षेत्र को हड़पने के लिए पड़ोसी राज्यों की मांग।

50. राज्य के राज्यपाल द्वारा किए जाने वाले कार्यों को सही क्रम में व्यवस्थित करें:
1. मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना।
2. मंत्रिपरिषद को पद की शपथ दिलाना।
3. नवनिर्वाचित विधानसभा का प्रथम सत्र आहूत करना।
4. विधानसभा में उद्घाटन भाषण देना।

(A) 1, 2, 3, 4
(B) 1, 3, 2, 4
(C) 3, 1, 2, 4
(D) 1, 2, 4, 3

51. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किसके द्वारा पद से हटाया जा सकता है?
(A) राज्य विधायिका की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा।
(B) कदाचार के आधार पर भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा।
(C) उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा।
(D) संसद में निर्धारित प्रक्रिया के बाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा।

52. चुनावी राजनीति के संदर्भ में, मध्य प्रदेश में 'मतदान व्यवहार' का तात्पर्य है:
(A) मतदाता किसी विशेष दल या उम्मीदवार को कैसे और क्यों चुनते हैं, इसका प्रतिरूप।
(B) चुनाव में मत डालने की प्रक्रिया।
(C) चुनावों को नियंत्रित करने वाला कानूनी ढांचा।
(D) मतों की गिनती की प्रक्रिया और परिणामों की घोषणा।

53. 1956 में मध्य प्रदेश का गठन किस व्यापक प्रक्रिया का हिस्सा था?
(A) भारत का क्षेत्रीय विस्तार।
(B) आर्थिक उदारीकरण।
(C) भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन।
(D) स्थानीय सरकारों को शक्ति का विकेंद्रीकरण।

NODIA

(C) मध्य प्रदेश विधानसभा
(D) भारत के राष्ट्रपति

10. मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
(A) विपक्ष के पास बहुमत द्वारा पारित किसी भी विधेयक को निषेध (वीटो) करने की शक्ति होती है।
(B) विपक्ष सरकार की नीतियों और कार्यों की जांच करता है।
(C) विपक्ष एक वैकल्पिक सरकार प्रदान करता है।
(D) विपक्ष विधानसभा में सार्वजनिक महत्व के मुद्दे उठाता है।

11. विधायी और कार्यकारी कार्यों की संवैधानिकता की समीक्षा करने की मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की शक्ति को किस रूप में जाना जाता है?
(A) न्यायिक सक्रियता
(B) न्यायिक निरीक्षण
(C) न्यायिक विवेक
(D) न्यायिक पुनरावलोकन

12. मध्य प्रदेश के राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
2. राज्यपाल पांच वर्ष के निश्चित कार्यकाल के लिए पद धारण करता है और उसे हटाया नहीं जा सकता।
3. राज्यपाल की आयु 35 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) केवल 1
(B) केवल 1 और 3
(C) केवल 2 और 3
(D) 1, 2 और 3

13. 1956 में मध्य प्रदेश के गठन का एक प्राथमिक निर्धारक किस आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन था?
(A) सरकारिया आयोग
(B) बलवंत राय मेहता समिति
(C) फजल अली आयोग
(D) साइमन कमीशन

14. मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की भूमिका का सबसे उपयुक्त वर्णन क्या है?
(A) राज्य का प्रमुख
(B) विधायिका का प्रमुख
(C) न्यायपालिका का प्रमुख
(D) सरकार का प्रमुख

15. मध्य प्रदेश में किसी विधेयक के कानून बनने की प्रक्रिया के दौरान होने वाली निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें:
1. राज्यपाल की सहमति
2. विधानसभा में प्रथम वाचन
3. विधेयक का पुरःस्थापन (पेश करना)
4. तृतीय वाचन और मतदान

(A) 3, 2, 4, 1
(B) 2, 3, 1, 4
(C) 3, 4, 2, 1
(D) 1, 2, 3, 4

16. निम्नलिखित में से किस कारक को मध्य प्रदेश की चुनावी राजनीति में मतदान व्यवहार का प्राथमिक निर्धारक माने जाने की संभावना सबसे कम है?
(A) जाति और समुदाय संबद्धता
(B) राष्ट्रीय विदेश नीति के मुद्दे
(C) वर्तमान सरकार का प्रदर्शन
(D) दलगत नेतृत्व का आकर्षण

17. मध्य प्रदेश विधानसभा का संगठन किन प्रावधानों द्वारा परिभाषित है?
(A) राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956
(B) भारत का संविधान
(C) राज्य मंत्रिमंडल का एक संकल्प
(D) लोकसभा की प्रक्रिया के नियम

18. मध्य प्रदेश के राज्यपाल की विधायी शक्तियों के संबंध में नीचे दो कथन दिए गए हैं:
कथन I: मध्य प्रदेश के राज्यपाल तब अध्यादेश प्रख्यापित कर सकते हैं जब विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा हो।
कथन II: राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश की शक्ति और प्रभाव राज्य विधायिका के अधिनियम के समान ही होता है।
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
(D) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।

19. वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश से अलग कर छत्तीसगढ़ का नया राज्य किसके माध्यम से बनाया गया था?
(A) राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 2000
(B) छत्तीसगढ़ राज्य का दर्जा अधिनियम, 2000
(C) मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000
(D) संविधान संशोधन अधिनियम, 2000

20. निम्नलिखित प्रश्न में, अभिकथन (A) के बाद कारण (R) दिया गया है। सही विकल्प चुनें:
अभिकथन (A): मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय को उन सभी क्षेत्रों के सभी न्यायालयों और न्यायाधिकरणों पर अधीक्षण की शक्ति है जिनके संबंध में वह अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है।
कारण (R): यह शक्ति उच्च न्यायालय को बिना किसी कानूनी आधार के अधीनस्थ न्यायपालिका के दैनिक कामकाज में सीधे हस्तक्षेप करने की अनुमति देती है।

Click Here to Buy book on Amazon

(A) प्रथम दृष्टया मत डाल सकते हैं।
(B) मतदान प्रक्रिया की निगरानी करते हैं और परिणाम घोषित करते हैं।
(C) मत से ठीक पहले बिना किसी कारण के सदस्यों को अयोग्य घोषित कर सकते हैं।
(D) राज्यपाल के निर्देशानुसार शक्ति परीक्षण कराने से मना कर सकते हैं।

66. निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख राजनीतिक दल नहीं है जिसने मध्य प्रदेश की दलीय व्यवस्था को महत्वपूर्ण रूप से आकार दिया है?
(A) भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
(B) भारतीय जनता पार्टी
(C) शुरुआती दशकों में समाजवादी विचारधारा वाले दल
(D) एक प्रमुख राज्य-विशिष्ट द्रविड़ दल

67. 1956 में राज्यों का पुनर्गठन जिसके कारण मध्य प्रदेश का गठन हुआ, किसकी सिफारिशों पर आधारित था?
(A) राज्य पुनर्गठन आयोग
(B) जेवीपी समिति
(C) धर आयोग
(D) वांचू समिति

68. मध्य प्रदेश के निर्धारकों और विशेषताओं पर विचार कीजिए:
1. यह एक भू-आबद्ध राज्य है।
2. इसमें अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण प्रतिशत है।
3. नर्मदा नदी इसके भूगोल और राजनीति की एक केंद्रीय विशेषता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) केवल 1
(B) केवल 1 और 2
(C) केवल 2 और 3
(D) 1, 2 और 3

69. मध्य प्रदेश में राज्य सरकार की विधि टीम का प्रमुख और मुख्य विधिक सलाहकार कौन होता है, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है?
(A) लोकायुक्त
(B) महाधिवक्ता
(C) मुख्य सचिव
(D) पुलिस महानिदेशक

70. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की निचली अदालतों के आदेशों के खिलाफ अपील सुनने की शक्ति क्या कहलाती है?
(A) मूल क्षेत्राधिकार
(B) रिट क्षेत्राधिकार
(C) अपीलीय क्षेत्राधिकार
(D) पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार

71. मध्य प्रदेश की चुनावी राजनीति में किसी दल की घोषित विकास परियोजनाओं से प्रभावित होने वाला मतदाता का निर्णय किसका उदाहरण है?
(A) पूर्वव्यापी मतदान
(B) मुद्दा-आधारित मतदान
(C) पहचान-आधारित मतदान
(D) करिश्माई मतदान

72. मध्य प्रदेश में मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है?
(A) राज्यपाल
(B) मुख्यमंत्री
(C) मुख्य सचिव
(D) सबसे वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री

73. मध्य प्रदेश विधानसभा किन सूचियों में वर्णित विषयों पर कानून बना सकती है?
(A) केवल संघ सूची
(B) राज्य सूची और समवर्ती सूची
(C) केवल समवर्ती सूची
(D) अवशिष्ट सूची

74. 1956 में मध्य प्रदेश का गठन कई अलग-अलग प्रशासनिक और राजनीतिक इकाइयों के विलय के परिणामस्वरूप हुआ था। निम्नलिखित में से कौन उनमें से एक नहीं था?
(A) मध्य भारत राज्य
(B) विंध्य प्रदेश राज्य
(C) भोपाल राज्य
(D) बॉम्बे प्रेसीडेंसी

75. निम्नलिखित प्रश्न में, अभिकथन (A) के बाद कारण (R) दिया गया है। सही विकल्प चुनें:
अभिकथन (A): मध्य प्रदेश विधानसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है।
कारण (R): मंत्रिपरिषद तब तक पद पर बनी रहती है जब तक उसे विधानसभा का विश्वास प्राप्त होता है।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

76. 2000 में मध्य प्रदेश का विभाजन उन राजनीतिक प्रक्रियाओं का परिणाम था जिन्होंने किस मुद्दे को उजागर किया था?
(A) आंतरिक उपनिवेशवाद और क्षेत्रीय असंतुलन।
(B) धार्मिक कट्टरवाद।
(C) भाषाई अंधराष्ट्रवाद।
(D) अंतर्राष्ट्रीय सीमा से निकटता।

77. मध्य प्रदेश के राज्यपाल किसका हिस्सा होते हैं?
(A) राज्य विधायिका

NODIA

32. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी आयु प्राप्त करने तक पद पर बने रहते हैं?
(A) 60 वर्ष
(B) 62 वर्ष
(C) 65 वर्ष
(D) 70 वर्ष

33. मध्य प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख निर्धारक कौन सा है?
(A) इसकी लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा।
(B) इसकी विशाल समुद्री स्थिति।
(C) इसकी बड़ी आदिवासी जनसंख्या और उससे जुड़ी राजनीति।
(D) एक सक्रिय अलगाववादी आंदोलन की उपस्थिति।

34. मध्य प्रदेश विधानसभा में धन विधेयक केवल किसकी पूर्व सिफारिश के साथ ही पेश किया जा सकता है?
(A) मुख्यमंत्री
(B) वित्त मंत्री
(C) विधानसभा अध्यक्ष
(D) राज्यपाल

35. निम्नलिखित प्रश्न में, अभिकथन (A) के बाद कारण (R) दिया गया है। सही विकल्प चुनें:
अभिकथन (A): राज्यपाल मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है।
कारण (R): राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और उनकी रिपोर्ट राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का आधार बन सकती है।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

36. मध्य प्रदेश के 2000 के विभाजन को बेहतर शासन और किस आधार पर उचित ठहराया गया था?
(A) सभी पड़ोसी राज्यों के साथ सांस्कृतिक समावेशन को बढ़ावा देना।
(B) आदिवासी दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्रों के लिए केंद्रित विकास।
(C) पूरे राज्य के लिए एक नई भाषाई नीति का कार्यान्वयन।
(D) शासन के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधि दायित्वों की पूर्ति।

37. मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद तब तक सत्ता में रहती है जब तक उसे किसका विश्वास प्राप्त होता है?
(A) राज्यपाल
(B) राष्ट्रपति
(C) मध्य प्रदेश विधानसभा
(D) मध्य प्रदेश के मतदाता

38. मध्य प्रदेश विधायिका में भूमिकाओं के संबंध में सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
सूची I: (पद)
P. अध्यक्ष
Q. मुख्यमंत्री
R. राज्यपाल
S. विपक्ष के नेता
सूची II: (प्राथमिक भूमिका)
1. सरकार का प्रमुख
2. सदन का पीठासीन अधिकारी
3. राज्य का प्रमुख
4. सबसे बड़े अल्पसंख्यक दल का प्रमुख
(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-2, Q-1, R-3, S-4
(C) P-3, Q-1, R-4, S-2
(D) P-2, Q-3, R-1, S-4

39. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार का विस्तार किस पर नहीं है?
(A) मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन।
(B) राज्य विधायिका के सदस्यों के चुनाव से संबंधित विवाद।
(C) संविधान की व्याख्या से जुड़े मामले।
(D) सत्र न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील।

40. निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश में दलीय व्यवस्था का सबसे अच्छा वर्णन करता है?
(A) एक-दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था।
(B) एक द्विध्रुवीय व्यवस्था जिसमें दो प्रमुख दल बारी-बारी से सत्ता में आते हैं।
(C) बार-बार गठबंधन सरकारों वाली बहु-दलीय व्यवस्था।
(D) निर्दलीय उम्मीदवारों के वर्चस्व वाली व्यवस्था।

41. यदि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद मृत्यु या त्यागपत्र के कारण रिक्त हो जाता है, तो तत्काल कार्यवाही क्या होती है?
(A) रिक्ति होने पर स्वतः ही राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है।
(B) सबसे वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री कार्यवाहक मुख्यमंत्री बन जाते हैं।
(C) विधानसभा भंग कर दी जाती है और तत्काल नए चुनाव कराए जाते हैं।
(D) सत्ताधारी दल राज्यपाल द्वारा नियुक्ति के लिए एक नेता का चुनाव करता है।

42. मध्य प्रदेश विधानसभा की मुख्य शक्ति है:
(A) उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और निष्कासन करना।
(B) राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाना।
(C) राज्य के लिए विदेश संबंध संचालित करना।

Downloaded from www.pdf.tube

(D) 1, 2 और 3

90. मध्य प्रदेश में राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच के संबंध का सबसे अच्छा वर्णन है:
(A) राज्यपाल सभी मामलों में मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधा होता है।
(B) विवेकाधीन मामलों को छोड़कर, राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करना चाहिए।
(C) मंत्रिपरिषद केवल एक सलाहकार निकाय है जिसका राज्यपाल पर कोई बाध्यकारी अधिकार नहीं है।
(D) राज्यपाल मंत्रिपरिषद का प्रत्यक्ष वरिष्ठ होता है।

91. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से किस निकाय के अध्यक्ष होते हैं?
(A) राज्य मानवाधिकार आयोग
(B) राज्य योजना बोर्ड
(C) मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय
(D) राज्य लोक सेवा आयोग

92. मध्य प्रदेश विधानसभा के संदर्भ में "त्रिशंकु विधानसभा" का तात्पर्य उस स्थिति से है जहाँ:
(A) विधानसभा कोई भी कार्य करने में असमर्थ हो।
(B) किसी भी एक दल या चुनाव पूर्व गठबंधन को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो।
(C) अध्यक्ष मध्य कार्यकाल में त्यागपत्र दे दे।
(D) विधानसभा भवन का नवीनीकरण चल रहा हो।

93. सूची I (शक्ति) को सूची II (मध्य प्रदेश में प्रयोग करने वाला प्राधिकारी) से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
सूची I:
P. क्षमादान देने की शक्ति
Q. अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति
R. मुख्यमंत्री नियुक्त करने की शक्ति
S. धन विधेयक को प्रमाणित करने की शक्ति
सूची II:
1. राज्यपाल
2. विधानसभा अध्यक्ष
(A) P-1, Q-1, R-1, S-2
(B) P-2, Q-1, R-1, S-2
(C) P-1, Q-2, R-2, S-1
(D) P-1, Q-1, R-2, S-2

94. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो मध्य प्रदेश का एक प्रमुख राजनीतिक दल है, पारंपरिक रूप से किस विचारधारा का समर्थन करती है?
(A) धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक लोकतंत्र
(B) इच्छातंत्रवाद
(C) जातीय-राष्ट्रवाद
(D) साम्यवाद

95. 1 नवंबर, 1956 को गठित मध्य प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र शामिल नहीं थे?
(A) संपूर्ण विंध्य प्रदेश
(B) मराठी भाषी विदर्भ क्षेत्र
(C) संपूर्ण भोपाल राज्य
(D) राजस्थान के कोटा जिले का सिरोंज उपखंड

96. मध्य प्रदेश के राज्यपाल की शक्तियों के संबंध में नीचे दो कथन दिए गए हैं:
कथन I: मध्य प्रदेश के राज्यपाल के पास विधानसभा को भंग करने की शक्ति है।
कथन II: इस शक्ति का प्रयोग किसी भी समय किया जा सकता है, भले ही सरकार को बहुमत प्राप्त हो, केवल राज्यपाल के व्यक्तिगत विवेक के आधार पर।
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
(D) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।

97. मंत्रिपरिषद के संगठन में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और कौन शामिल होते हैं?
(A) संसदीय सचिव
(B) क्षेत्रीय परिषद के सदस्य
(C) उप मंत्री
(D) जिला कलेक्टर

98. मध्य प्रदेश विधानसभा की प्राथमिक संवैधानिक भूमिका क्या है?
(A) विधायिका के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करना।
(B) जनता के प्रति न्यायपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करना।
(C) राष्ट्रपति के प्रति राज्यपाल की जवाबदेही सुनिश्चित करना।
(D) केंद्र सरकार के प्रति राज्य की जवाबदेही सुनिश्चित करना।

99. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थायी खंडपीठ इंदौर और कहाँ स्थित हैं?
(A) ग्वालियर
(B) भोपाल
(C) उज्जैन
(D) रीवा

100. निम्नलिखित प्रश्न में, अभिकथन (A) के बाद कारण (R) दिया गया है। सही विकल्प चुनें:
अभिकथन (A): मध्य प्रदेश में चुनावी राजनीति विकास के मुद्दों और शासन के प्रदर्शन से प्रभावित होती है।
कारण (R): राज्य के मतदाता प्रदर्शन की परवाह किए बिना, केवल जातिगत पहचान के आधार पर लगातार एक ही दल को मत देते हैं।

NODIA

124. मध्य प्रदेश में संवैधानिक तंत्र के विफल होने की स्थिति में, राज्यपाल राष्ट्रपति को क्या लागू करने की सिफारिश कर सकते हैं?
(A) अनुच्छेद 34 के तहत सैन्य शासन
(B) अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल
(C) अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल
(D) अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन

125. मध्य प्रदेश मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके प्रसादपर्यंत पद धारण करते हैं?
(A) राज्यपाल
(B) मुख्यमंत्री
(C) विधानसभा अध्यक्ष
(D) राष्ट्रपति

126. सूची I (शब्दावली) को सूची II (विधायी संदर्भ में अर्थ) से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
सूची I:
P. सत्रावसान
Q. स्थगन
R. विघटन
S. गणपूर्ति
सूची II:
1. वर्तमान सदन के कार्यकाल को ही समाप्त कर देता है
2. सदन की एक बैठक की समाप्ति
3. सदन के एक सत्र की समाप्ति
4. उपस्थित रहने वाले सदस्यों की न्यूनतम संख्या
(A) P-3, Q-2, R-1, S-4
(B) P-1, Q-2, R-3, S-4
(C) P-3, Q-4, R-1, S-2
(D) P-2, Q-3, R-4, S-1

127. निम्नलिखित में से कौन सी मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष की मान्यता प्राप्त भूमिका नहीं है?
(A) सरकार की विफलताओं और कमियों को उजागर करना।
(B) राज्यपाल को त्यागपत्र देने के लिए विवश करना।
(C) अपने सदस्यों को भविष्य की मंत्री पद की जिम्मेदारियों के लिए तैयार करना।
(D) उन मतदाताओं के विचारों का प्रतिनिधित्व करना जिन्होंने सरकार को मत नहीं दिया।

128. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा जारी 'परमादेश' की रिट एक सार्वजनिक अधिकारी को दिया गया आदेश है:
(A) किसी ऐसे व्यक्ति को रिहा करना जिसे अवैध रूप से हिरासत में लिया गया हो।
(B) किसी ऐसे आधिकारिक कर्तव्य का पालन करना जिसे निभाने में वे विफल रहे हों या मना कर दिया हो।
(C) निचली अदालत में कार्यवाही रोकना।
(D) यह सिद्ध करना कि वे किस अधिकार से सार्वजनिक पद धारण करते हैं।

129. 2000 में मध्य प्रदेश का विभाजन किस आधार पर एक अलग राज्य की लंबे समय से चली आ रही मांग की प्रतिक्रिया थी?
(A) छत्तीसगढ़ की विशिष्ट सांस्कृतिक और प्रशासनिक पहचान।
(B) दक्षिणी राज्य क्षेत्रों में बोली जाने वाली विभिन्न भाषाएँ।
(C) संयुक्त राष्ट्र में पृथक्करण के लिए कराया गया औपचारिक मतदान।
(D) पड़ोसी संप्रभु देश के साथ हस्ताक्षरित एक द्विपक्षीय समझौता।

130. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को नियुक्त करने की राज्यपाल की शक्ति है एक:
(A) विधायी शक्ति
(B) न्यायिक शक्ति
(C) कार्यकारी शक्ति
(D) वित्तीय शक्ति

131. मध्य प्रदेश मंत्रिपरिषद के सदस्यों के लिए अनिवार्य है कि वे:
(A) राज्य विधायिका के सदस्य हों।
(B) राज्यपाल द्वारा नामित हों।
(C) सेवानिवृत्त सिविल सेवक हों।
(D) 40 वर्ष से अधिक आयु के हों।

132. मध्य प्रदेश विधानसभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह एक एकसदनीय विधायिका है।
2. इसके सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं।
3. राज्यपाल आंग्ल-भारतीय समुदाय के सदस्यों को नामित कर सकते हैं यदि उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व न हो।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3

133. मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है?
(A) विधानसभा के सदस्यों द्वारा अपने बीच में से।
(B) राज्यपाल द्वारा।
(C) मुख्यमंत्री द्वारा।
(D) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा।

134. मध्य प्रदेश के मुख्य राजनीतिक दल, जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, किसके उदाहरण हैं?
(A) क्षेत्रीय दल
(B) राष्ट्रीय दल
(C) अलगाववादी दल
(D) एकल-मुद्दा आधारित दल

135. मूल, अविभाजित मध्य प्रदेश राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था?

Click Here to Buy book on Amazon

(B) जब किसी मामले पर सदन समान रुप से विभाजित हो।
(C) जब अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है।
(D) जब बजट पेश किया जाता है।

113. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु है:
(A) 62 वर्ष
(B) 60 वर्ष
(C) 65 वर्ष
(D) 58 वर्ष

114. "चुनावी राजनीति" शब्द मुख्य रूप से किस प्रक्रिया को संदर्भित करता है?
(A) निर्वाचन आयोग का कामकाज।
(B) चुनाव लड़ना और सरकार बनाना।
(C) सरकारी नीतियों का निर्माण।
(D) अदालतों द्वारा चुनाव विवादों का न्यायनिर्णयन।

115. मध्य प्रदेश की राजनीति के इतिहास में निम्नलिखित संस्थाओं/घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें:
1. भोपाल राज्य का भारतीय संघ में विलय।
2. मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम का पारित होना, जिससे छत्तीसगढ़ बना।
3. राज्य पुनर्गठन अधिनियम का पारित होना, जिससे मध्य प्रदेश बना।
4. मध्य भारत राज्य का गठन।
(A) 4, 1, 3, 2
(B) 1, 4, 3, 2
(C) 4, 3, 1, 2
(D) 1, 3, 4, 2

116. मध्य प्रदेश के भूगोल की एक महत्वपूर्ण विशेषता जो इसकी राजनीति और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है, वह किसकी उपस्थिति है?
(A) व्यापार को सुगम बनाने वाली एक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा।
(B) नर्मदा, ताप्ती और चंबल जैसी कई प्रमुख नदी घाटियाँ।
(C) बारहमासी नदियाँ प्रदान करने वाले प्रमुख हिम आच्छादित पर्वत।
(D) थार जैसा विशाल मरुस्थलीय क्षेत्र।

117. मध्य प्रदेश के राज्यपाल की विधिक स्थिति के संबंध में नीचे दो कथन दिए गए हैं:
कथन I: मध्य प्रदेश का राज्यपाल अपने पद की शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं है।
कथन II: राज्यपाल को अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी आपराधिक कार्यवाही से व्यक्तिगत उन्मुक्ति प्राप्त है।
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
(D) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।

118. मध्य प्रदेश में वास्तविक कार्यकारी शक्ति किसमें निहित है?
(A) मुख्यमंत्री
(B) राज्यपाल
(C) मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद
(D) मुख्य सचिव

119. मध्य प्रदेश विधानसभा का एक प्रमुख कार्य राज्य के वित्त पर नियंत्रण रखना है। यह मुख्य रूप से किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है?
(A) सदन की एक समिति द्वारा खातों का लेखा-परीक्षण करना।
(B) बजट पारित करने के माध्यम से सभी खर्चों को अधिकृत करना।
(C) राज्य के वित्त सचिव की नियुक्ति करना।
(D) नागरिकों से सीधे कर वसूल करना।

120. निम्नलिखित प्रश्न में, अभिकथन (A) के बाद कारण (R) दिया गया है। सही विकल्प चुनें:
अभिकथन (A): मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष की भूमिका सत्तारूढ़ सरकार पर नियंत्रण और संतुलन प्रदान करना है।
कारण (R): संसदीय लोकतंत्र में, सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक रचनात्मक विपक्ष आवश्यक है।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

121. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है?
(A) मध्य प्रदेश के राज्यपाल।
(B) भारत के राष्ट्रपति।
(C) मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री।
(D) भारत के मुख्य न्यायाधीश।

122. मध्य प्रदेश में मतदाताओं द्वारा विधानसभा और राष्ट्रीय संसदीय चुनावों के लिए अलग-अलग दलों को चुनने की घटना को क्या कहा जाता है?
(A) विभाजित मत (स्प्लिट-टिकट वोटिंग)
(B) प्रत्यक्ष मत
(C) सामरिक मत
(D) विरोध मत

123. 1956 में गठित मूल मध्य प्रदेश राज्य निम्नलिखित में से किसे छोड़कर अन्य क्षेत्रों को मिलाकर बनाया गया था?
(A) तत्कालीन मध्य प्रांत एवं बरार।
(B) हैदराबाद के निज़ाम का क्षेत्र।
(C) मध्य भारत की रियासतें।
(D) विंध्य प्रदेश राज्य।

Downloaded from www.pdf.tube

(D) उच्च न्यायालय प्रशासन

148. "न्यायिक पुनरावलोकन" की अवधारणा उच्च न्यायालय को शक्ति प्रदान करती है:
(A) एक तयशुदा मामले में साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन करना।
(B) किसी कानून या कार्यकारी आदेश की संवैधानिकता की जांच करना।
(C) राज्य विधायिका के कामकाज की निगरानी करना।
(D) विधिक मामलों पर राज्यपाल को सलाह देना।

149. मध्य प्रदेश में दलीय व्यवस्था पर हावी होने वाले दो मुख्य राष्ट्रीय दल कौन से हैं?
(A) भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
(B) भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी
(C) भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और समाजवादी पार्टी
(D) भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी)

150. सूची I. (घटना) को सूची II. (वर्ष) से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
सूची I:
P. मध्य प्रदेश का गठन
Q. मध्य प्रदेश का विभाजन
R. राज्य पुनर्गठन अधिनियम का अधिनियमन
S. छत्तीसगढ़ राज्य का गठन
सूची II:
1. 2000
2. 1956
(A) P-2, Q-1, R-2, S-1
(B) P-1, Q-2, R-1, S-2
(C) P-2, Q-1, R-1, S-2
(D) P-1, Q-2, R-2, S-1

151. मध्य प्रदेश के राज्यपाल उस तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करते हैं जिस दिन वे:
(A) अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करते हैं।
(B) राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं।
(C) राज्य विधायिका द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं।
(D) पद की शपथ लेते हैं।

152. मध्य प्रदेश में मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन किसका विशेषाधिकार है?
(A) मुख्यमंत्री
(B) राज्यपाल
(C) विधानसभा अध्यक्ष
(D) राज्य विधायिका

153. यदि मध्य प्रदेश में विधानसभा के किसी गैर-सदस्य को मंत्री नियुक्त किया जाता है तो क्या होता है?
(A) उन्हें छह महीने के भीतर विधानसभा के लिए निर्वाचित होना होगा।
(B) वे पूर्ण कार्यकाल के लिए मंत्री बने रह सकते हैं।
(C) नियुक्ति को असंवैधानिक और शून्य माना जाता है।
(D) वे केवल उप मंत्री हो सकते हैं, कैबिनेट मंत्री नहीं।

154. विधानसभा भंग होने के बाद भी अध्यक्ष तब तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक:
(A) नई सरकार का गठन न हो जाए।
(B) राष्ट्रपति अधिसूचना जारी न कर दें।
(C) नई विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पहले तक।
(D) निर्वाचन आयोग चुनाव परिणामों की घोषणा न कर दे।

NODIA

155. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की बंदी प्रत्यक्षीकरण और परमादेश जैसी रिट जारी करने की शक्ति किस उद्देश्य के लिए है?
(A) मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन और किसी अन्य उद्देश्य के लिए।
(B) केवल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए।
(C) केवल कानूनी अधिकारों के प्रवर्तन के लिए।
(D) उच्चतम न्यायालय के निर्णयों की समीक्षा के लिए।

156. मध्य प्रदेश में प्रतिस्पर्धी दो-दलीय व्यवस्था किसमें योगदान देती है?
(A) राष्ट्रपति शासन का बार-बार लगना।
(B) सत्ता का नियमित परिवर्तन और मजबूत चुनावी प्रतिस्पर्धा।
(C) सरकारों के भीतर उच्च स्तर की राजनीतिक स्थिरता।
(D) सरकार बनाने में निर्दलीय उम्मीदवारों का दबदबा।

157. किस आयोग की रिपोर्ट राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 का आधार थी?
(A) सरकारिया आयोग
(B) फजल अली आयोग
(C) कोठारी आयोग
(D) मंडल आयोग

158. मध्य प्रदेश में राज्यपाल की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए:
1. राज्यपाल किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है।
2. राज्यपाल मृत्युदंड के मामलों में क्षमादान दे सकता है।
3. राज्यपाल आम चुनाव के बाद विधानसभा के पहले सत्र को संबोधित करता है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) केवल 1 और 3
(B) केवल 2
(C) केवल 1 और 2
(D) 1, 2 और 3

159. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को किसके द्वारा हटाया जा सकता है?
(A) विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव द्वारा।

(A) 1956
(B) 1947
(C) 1950
(D) 2000

136. मध्य प्रदेश राज्य के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है?
(A) मध्य प्रदेश के राज्यपाल
(B) भारत के राष्ट्रपति
(C) मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
(D) मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री

137. निम्नलिखित में से कौन सी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की भूमिका नहीं है?
(A) राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष।
(B) राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच संचार का मुख्य माध्यम।
(C) अंतर-राज्यीय परिषद के प्रमुख।
(D) सदन के नेता (यदि विधानसभा सदस्य हों)।

138. मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य कितनी अवधि के लिए चुने जाते हैं?
(A) 5 वर्ष
(B) 4 वर्ष
(C) 6 वर्ष
(D) 3 वर्ष

139. यदि मध्य प्रदेश में राज्य विधायिका की संयुक्त बैठक होती, तो उसकी अध्यक्षता कौन करता?
(A) राज्यपाल
(B) मुख्यमंत्री
(C) विधानसभा अध्यक्ष
(D) विधान परिषद के सभापति

140. निम्नलिखित प्रश्न में, अभिकथन (A) के बाद कारण (R) दिया गया है। सही विकल्प चुनें:
अभिकथन (A): मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पास अपीलीय क्षेत्राधिकार है।
कारण (R): यह दीवानी और आपराधिक दोनों मामलों में मध्य प्रदेश के भीतर अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुन सकता है।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

141. मध्य प्रदेश के शहरी निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान व्यवहार के किससे प्रभावित होने की अधिक संभावना है?
(A) पारंपरिक जाति पदानुक्रम।
(B) बुनियादी ढांचे, सुशासन और मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं जैसे मुद्दे।
(C) सामंती निष्ठा।
(D) ग्राम प्रधान की राय।

142. 1956 में राज्य पुनर्गठन की प्रक्रिया किस आधार पर भारत के राजनीतिक मानचित्र को फिर से तैयार करने के लिए शुरू की गई थी?
(A) आर्थिक विकास
(B) भाषाई आधार
(C) प्रशासनिक सुविधा
(D) सैन्य रणनीति

143. 2000 के विभाजन के बाद, मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ रही?
(A) इंदौर
(B) जबलपुर
(C) भोपाल
(D) ग्वालियर

144. मध्य प्रदेश के राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों के संबंध में नीचे दो कथन दिए गए हैं:
कथन I: मध्य प्रदेश के राज्यपाल राज्य के कानून के विरुद्ध किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति की सजा को क्षमा, प्रविलंबन या कम कर सकते हैं।
कथन II: राज्यपाल की क्षमादान शक्ति पूर्ण है और इसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
(D) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।

145. मध्य प्रदेश में पूरी मंत्रिपरिषद को किसके द्वारा पद से हटाया जा सकता है?
(A) लोकसभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव।
(B) भारत के राष्ट्रपति के एक निर्देश।
(C) विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होना।
(D) मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का एक निर्णय।

146. समवर्ती सूची के विषय पर मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा बनाया गया कानून संघ के कानून के प्रतिकूल है। कौन सा कानून प्रभावी होगा?
(A) राज्य का कानून, यदि उसे राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हो गई हो।
(B) राज्य का कानून।
(C) संघ का कानून।
(D) वह कानून जो पहले अधिनियमित किया गया था।

147. "छाया मंत्रिमंडल" एक अवधारणा है जो किससे जुड़ी है?
(A) राज्यपाल सचिवालय
(B) विपक्ष की भूमिका
(C) मुख्यमंत्री कार्यालय

Click Here to Buy book on Amazon

(C) राज्य निर्वाचन आयोग
(D) गृह मंत्रालय

196. मध्य प्रदेश को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विभाजित किया गया था?
(A) अनुच्छेद 3
(B) अनुच्छेद 368
(C) अनुच्छेद 356
(D) अनुच्छेद 1

197. निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति मध्य प्रदेश के राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है?
(A) मुख्यमंत्री
(B) महाधिवक्ता
(C) राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष
(D) उच्च न्यायालय के न्यायाधीश

198. मध्य प्रदेश में मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या को संवैधानिक रूप से एक संशोधन द्वारा सीमित किया गया है ताकि किसे रोका जा सके?
(A) अनावश्यक रूप से बड़े मंत्रिमंडल और राजनीतिक अनैतिक दलबदल।
(B) एक ही दल का प्रभुत्व।
(C) राज्यपाल के पास बहुत अधिक शक्ति होना।
(D) विपक्ष का बहुत कमजोर होना।

199. वह प्राथमिक तरीका क्या है जिसके माध्यम से मध्य प्रदेश विधानसभा कार्यपालिका की वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करती है?
(A) लोक लेखा समिति के माध्यम से
(B) सीधे राज्य के खजाने का प्रबंधन करके
(C) राष्ट्रपति को राज्यपाल की रिपोर्ट के माध्यम से
(D) नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करके

200. विधायिका में "विपक्ष के नेता" की अवधारणा को आधिकारिक तौर पर मान्यता क्यों दी गई है?
(A) विपक्ष के सबसे बड़े दल को औपचारिक दर्जा और भूमिका प्रदान करने के लिए।
(B) मुख्यमंत्री के सामने सत्ता का एक वैकल्पिक केंद्र बनाने के लिए।
(C) यह सुनिश्चित करने के लिए कि सरकार को हमेशा आलोचना का सामना करना पड़े।
(D) गठबंधन सरकार बनाने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए।

201. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किसके परामर्श से की जाती है?
(A) भारत के मुख्य न्यायाधीश और मध्य प्रदेश के राज्यपाल।
(B) प्रधानमंत्री और केंद्रीय विधि मंत्री।
(C) मध्य प्रदेश की राज्य विधायिका।
(D) भारतीय विधिक परिषद (बार काउंसिल ऑफ इंडिया)।

202. मध्य प्रदेश में दलीय व्यवस्था की विशेषता है:
(A) दो राष्ट्रीय दलों का प्रभुत्व।
(B) किसी भी राष्ट्रीय दल की अनुपस्थिति।
(C) गठबंधन सरकारों की एक मजबूत परंपरा।
(D) एक शक्तिशाली क्षेत्रीय दल जो सरकार गठन का निर्धारण करता है।

NODIA

203. 1956 में मध्य प्रदेश के गठन के बाद किस शहर को इसकी राजधानी बनाया गया?
(A) नागपुर
(B) जबलपुर
(C) भोपाल
(D) इंदौर

204. मध्य प्रदेश की राजनीतिक विशेषताओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. इसकी एकसदनीय विधायिका है।
2. राज्य लोकसभा और राज्यसभा दोनों में प्रतिनिधि भेजता है।
3. राज्यपाल राज्य का प्रमुख होता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3

205. राज्यपाल की राज्य के संवैधानिक प्रमुख और किसके रूप में 'दोहरी भूमिका' होती है?
(A) केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में।
(B) राज्य की जनता के प्रतिनिधि के रूप में।
(C) राज्य न्यायपालिका के सदस्य के रूप में।
(D) राज्य में सत्तारूढ़ दल के नेता के रूप में।

206. मध्य प्रदेश में मंत्रिपरिषद का संगठन किस मॉडल पर आधारित है?
(A) ब्रिटिश संसदीय प्रणाली।
(B) संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रपति प्रणाली।
(C) स्विस सामूहिक कार्यकारी प्रणाली।
(D) फ्रांसीसी अर्ध-राष्ट्रपति प्रणाली।

207. मध्य प्रदेश विधानसभा की शक्तियों के बारे में कौन सा कथन गलत है?
(A) यह संविधान के उल्लंघन के लिए राज्यपाल पर महाभियोग चला सकती है।
(B) यह मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सकती है।
(C) इसका राज्य के वित्त पर नियंत्रण होता है।
(D) यह राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है।

(B) राज्यपाल द्वारा अपने विवेक से।
(C) राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा।
(D) संविधान का उल्लंघन करने पर उच्च न्यायालय द्वारा।

160. मध्य प्रदेश विधानसभा का संगठन, जिसमें इसकी संरचना, अवधि और अधिकारी शामिल हैं, मुख्य रूप से किसके द्वारा शासित होता है?
(A) लोकसभा की प्रक्रिया के नियम।
(B) राष्ट्रपति के अध्यादेश।
(C) भारत का संविधान (अनुच्छेद 168-212)।
(D) नीति आयोग के संकल्प।

161. मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता को किसका दर्जा और सुविधाएं प्राप्त होती हैं?
(A) उप मंत्री
(B) कैबिनेट मंत्री
(C) राज्य मंत्री
(D) सरकार के सचिव

162. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं?
(A) राज्य विधायिका
(B) भारत की संसद
(C) मुख्यमंत्री के परामर्श से राज्यपाल
(D) राज्य की संचित निधि

163. मध्य प्रदेश की चुनावी राजनीति के संदर्भ में "सत्ता-विरोधी लहर" शब्द का अर्थ है:
(A) सत्तारूढ़ दल के पक्ष में एक भावना।
(B) सत्तारूढ़ दल या वर्तमान प्रतिनिधि के विरुद्ध एक भावना।
(C) निर्दलीय उम्मीदवारों के समर्थन की लहर।
(D) उच्च मतदान प्रतिशत।

164. 1956 में मध्य प्रदेश का निर्माण किस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था?
(A) रियासतों का उन्मूलन।
(B) मध्य भारत में प्रशासनिक सीमाओं का एकीकरण और युक्तिकरण।
(C) भारत का उत्तर और दक्षिण में विभाजन।
(D) सरकार के एकात्मक स्वरूप की स्थापना।

165. निम्नलिखित प्रश्न में, अभिकथन (A) के बाद कारण (R) दिया गया है। सही विकल्प चुनें:
अभिकथन (A): मध्य प्रदेश में मंत्रिपरिषद सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करती है।
कारण (R): यदि किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

166. मध्य प्रदेश विधानसभा में पेश किया गया धन विधेयक:
(A) अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक के रूप में प्रमाणित होना आवश्यक है।
(B) राज्यपाल द्वारा अस्वीकार किया जा सकता है।
(C) विधायिका के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है।
(D) पेश करने के लिए राज्यपाल की सिफारिश की आवश्यकता नहीं होती।

167. मध्य प्रदेश के राज्यपाल की मुख्य भूमिका किसके रूप में कार्य करना है?
(A) केंद्र सरकार का एक अभिकर्ता।
(B) संघ और राज्य के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी।
(C) राज्य का मुख्य कार्यकारी।
(D) राज्य पुलिस बलों का प्रधान सेनापति।

168. यदि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री नियुक्ति के समय विधानसभा का सदस्य नहीं है, तो उन्हें:
(A) छह महीने के भीतर विधानसभा के लिए निर्वाचित होना होगा।
(B) तुरंत त्यागपत्र देना होगा।
(C) राज्यपाल द्वारा विधानसभा में मनोनीत होना होगा।
(D) 30 दिनों के भीतर विश्वास मत हासिल करना होगा।

169. मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र बुलाने की शक्ति किसमें निहित है?
(A) विधानसभा अध्यक्ष
(B) मुख्यमंत्री
(C) राज्यपाल
(D) सदन के नेता

170. निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्षी दल का नहीं है?
(A) बजट की जांच करना।
(B) सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति करना।
(C) विधायी बहसों में भाग लेना।
(D) सार्वजनिक महत्व के मामले उठाना।

171. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार और शक्तियाँ मुख्य रूप से किसके द्वारा परिभाषित हैं?
(A) राज्य विधायिका
(B) भारत का संविधान
(C) राज्यपाल
(D) मुख्यमंत्री

Downloaded from www.pdf.tube

(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

101. 2000 में मध्य प्रदेश के विभाजन के बाद, राज्य की विधानसभा में सीटों की संख्या:
(A) घट गई।
(B) काफी बढ़ गई।
(C) अपरिवर्तित रही।
(D) द्विसदनीय विधायिका के पक्ष में समाप्त कर दी गई।

102. मध्य प्रदेश के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसकी सलाह पर की जाती है?
(A) केंद्रीय मंत्रिपरिषद
(B) भारत के मुख्य न्यायाधीश
(C) निवर्तमान राज्यपाल
(D) मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री

103. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में कौन सा कथन गलत है?
(A) मुख्यमंत्री मत बराबर होने की स्थिति में विधानसभा में निर्णायक मत डाल सकता है।
(B) मुख्यमंत्री राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच संचार का माध्यम है।
(C) मुख्यमंत्री विधानसभा को भंग करने के लिए राज्यपाल को सलाह देता है।
(D) मुख्यमंत्री राज्य सरकार का प्रमुख होता है।

104. निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश की विधायिका का हिस्सा है लेकिन विधानसभा का सदस्य नहीं है?
(A) राज्यपाल
(B) मुख्यमंत्री
(C) विधानसभा अध्यक्ष
(D) महाधिवक्ता

105. राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति में, विपक्ष की भूमिका क्या होती है?
(A) चुनावों से बचने के लिए तुरंत सत्तारूढ़ दल का समर्थन करना।
(B) सरकार बनाने के लिए खुद को एक व्यवहार्य विकल्प के रूप में प्रस्तुत करना।
(C) विकल्प तलाशे बिना विधानसभा भंग करने की मांग करना।
(D) न्यायपालिका से प्रशासन संभालने का अनुरोध करना।

106. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत या न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए किस रिट का प्रयोग किया जाता है?
(A) बंदी प्रत्यक्षीकरण
(B) परमादेश
(C) उत्प्रेषण (सर्टियोरारी)
(D) अधिकार-पृच्छा

107. मध्य प्रदेश में दलीय व्यवस्था को प्रतिस्पर्धी के रूप में जाना जा सकता है, जहाँ सत्ता मुख्य रूप से किन दो दलों के बीच स्थानांतरित हुई है?
(A) भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी
(B) भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय जनता पार्टी
(C) भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी
(D) भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी

108. राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956, जिसने मध्य प्रदेश राज्य बनाया, किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था?
(A) भारत की संसद
(B) भारत की संविधान सभा
(C) यूनाइटेड किंगडम की सरकार
(D) सभी राज्य विधानसभाओं का संयुक्त सत्र

109. निम्नलिखित में से किसे मध्य प्रदेश के राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति माना जाता है?
(A) राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करना।
(B) महाधिवक्ता की नियुक्ति करना।
(C) विधानसभा द्वारा पारित एक साधारण विधेयक को सहमति देना।
(D) प्रशासन के संबंध में मुख्यमंत्री से जानकारी मांगना।

110. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए:
1. वह राज्यपाल का मुख्य सलाहकार होता है।
2. वह मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन और फेरबदल करता है।
3. वह राज्यपाल को किसी मंत्री की पदच्युति की सिफारिश कर सकता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3

111. मध्य प्रदेश विधानसभा के संदर्भ में 'गणपूर्ति' (कोरम) शब्द का तात्पर्य है:
(A) कार्यवाही संचालित करने के लिए उपस्थित होने हेतु आवश्यक सदस्यों की न्यूनतम संख्या।
(B) किसी विधेयक पर बोलने की अनुमति प्राप्त सदस्यों की अधिकतम संख्या।
(C) संविधान संशोधन के लिए आवश्यक दो-तिहाई बहुमत।
(D) प्रश्नकाल की अवधि।

112. मध्य प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष निर्णायक मत का प्रयोग कब करता है?
(A) जब कोई विधेयक पेश किया जाता है।

NODIA

(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
(D) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।

184. मध्य प्रदेश के राज्यपाल को मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह:
(A) की किसी भी न्यायालय द्वारा जांच नहीं की जा सकती।
(B) की किसी भी न्यायालय द्वारा जांच की जा सकती है।
(C) की केवल उच्चतम न्यायालय द्वारा जांच की जा सकती है।
(D) राज्यपाल पर बाध्यकारी नहीं है।

185. मध्य प्रदेश विधानसभा के संगठन के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए:
1. यह राज्य विधायिका का निचला सदन है।
2. अध्यक्ष इसका मुख्य पीठासीन अधिकारी होता है।
3. यह एक स्थायी निकाय है और इसका विघटन नहीं किया जा सकता।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 3
(D) 1, 2 और 3

186. विपक्ष के नेता के प्राथमिक कार्यों में से एक है:
(A) सभी सरकारी प्रस्तावों पर सहमत होकर सदन का सुचारु संचालन सुनिश्चित करना।
(B) एक वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रदान करना और सरकार के कार्यों पर नियंत्रण रखना।
(C) राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच संपर्क के रूप में कार्य करना।
(D) विभिन्न सदन समितियों में सदस्यों को नामित करना।

187. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किसके परामर्श के बाद की जाती है?
(A) भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल।
(B) केवल राज्य के मुख्यमंत्री।
(C) भारत के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के राज्यपाल और राज्य की मंत्रिपरिषद।
(D) केवल उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम।

188. मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में चुनावी परिणामों को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक कौन सा है?
(A) शहरी बुनियादी ढांचे का विकास।
(B) वन अधिकार, भूमि हस्तांतरण और सामुदायिक पहचान से संबंधित मुद्दे।
(C) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीतियां।
(D) राज्य की सूचना प्रौद्योगिकी नीति।

189. मध्य प्रदेश की राजनीति के 'निर्धारक' किसे संदर्भित करते हैं?
(A) भूगोल, समाज और अर्थव्यवस्था जैसे मूलभूत कारक जो इसके राजनीतिक जीवन को आकार देते हैं।
(B) अंतिम चुनाव परिणाम।
(C) राज्य के लिए संवैधानिक प्रावधान।
(D) राजनीतिक मामलों पर उच्च न्यायालय के निर्णय।

190. निम्नलिखित प्रश्न में, अभिकथन (A) के बाद कारण (R) दिया गया है। सही विकल्प चुनें:
अभिकथन (A): मध्य प्रदेश के राज्यपाल के पास राज्य विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करने की शक्ति है।
कारण (R): इस शक्ति का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई विधेयक राज्य उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालता है या व्यापक राष्ट्रीय हित के विरुद्ध होता है।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

191. मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों के वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है?
(A) राज्यपाल
(B) राज्य विधायिका
(C) राष्ट्रपति
(D) संसद

192. मध्य प्रदेश में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कहाँ पेश किया जा सकता है?
(A) केवल विधानसभा में।
(B) विधानसभा और राज्यसभा दोनों में।
(C) मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में।
(D) राज्य विधायिका के किसी भी सदन में, यदि वह द्विसदनीय होती।

193. मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष की भूमिका किसके समान है?
(A) भारत के प्रधानमंत्री
(B) लोकसभा के अध्यक्ष
(C) भारत के राष्ट्रपति
(D) भारत के मुख्य न्यायाधीश

194. निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का हिस्सा नहीं है?
(A) मूल क्षेत्राधिकार
(B) राज्यपाल को सलाह देने का क्षेत्राधिकार
(C) अपीलीय क्षेत्राधिकार
(D) पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार

195. राज्य विधायिका के चुनावों के संचालन सहित मध्य प्रदेश में चुनावी प्रक्रिया की निगरानी किसके द्वारा की जाती है?
(A) भारत निर्वाचन आयोग
(B) राज्य सरकार

Click Here to Buy book on Amazon

172. दो प्रमुख राजनीतिक दलों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की उपस्थिति, मध्य प्रदेश की दलीय व्यवस्था को काफी हद तक बनाती है:
(A) द्विध्रुवीय
(B) बहु-ध्रुवीय
(C) एक-ध्रुवीय
(D) गैर-दलीय

173. राज्य पुनर्गठन आयोग (1953) की अध्यक्षता किसने की थी?
(A) एच. एन. कुंजरू
(B) फजल अली
(C) के. एम. पणिक्कर
(D) वल्लभभाई पटेल

174. 2000 के बाद के मध्य प्रदेश की विशेषताओं को आकार देने वाला एक प्रमुख 'निर्धारक' क्या था?
(A) छत्तीसगढ़ को अपने खनिज समृद्ध क्षेत्रों का हस्तांतरण।
(B) नए तटीय क्षेत्रों की प्राप्ति।
(C) कृषि आधारित अर्थव्यवस्था से पूर्णतः औद्योगिक अर्थव्यवस्था में बदलाव।
(D) एक नई आधिकारिक भाषा को अपनाना।

175. राज्य व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित को भारत के संविधान में उनके आने वाले क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें:
1. राज्यपाल
2. मंत्रिपरिषद
3. राज्य विधायिका
4. राज्यों के लिए उच्च न्यायालय
(A) 1, 2, 3, 4
(B) 1, 3, 2, 4
(C) 2, 1, 3, 4
(D) 3, 1, 2, 4

176. मध्य प्रदेश का राज्यपाल केवल तभी अध्यादेश जारी कर सकता है जब:
(A) राज्य विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा हो।
(B) मुख्यमंत्री ऐसा करने की सलाह दें।
(C) भारत के राष्ट्रपति अनुमति दें।
(D) उच्च न्यायालय किसी कानून की आवश्यकता को प्रमाणित करे।

177. मध्य प्रदेश की मंत्रिपरिषद किनसे मिलकर बनी है?
(A) कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री।
(B) केवल कैबिनेट मंत्री।
(C) कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री।
(D) केवल सत्तारूढ़ दल के सदस्य।

178. मध्य प्रदेश विधानसभा की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति इसकी:
(A) न्यायिक शक्ति है
(B) कार्यकारी शक्ति है
(C) विधायी और वित्तीय शक्तियाँ हैं
(D) वित्तीय शक्ति है

179. मध्य प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष, अध्यक्ष के कर्तव्यों का पालन तब करते हैं जब पद:
(A) सत्र में हो
(B) रिक्त हो
(C) सत्रावसान हो गया हो
(D) अवकाश में हो

180. सूची I (क्षेत्राधिकार) को सूची II (मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय से संबंधित विवरण) से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
सूची I:
P. मूल क्षेत्राधिकार
Q. अपीलीय क्षेत्राधिकार
R. पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार
S. रिट क्षेत्राधिकार
सूची II:
1. निचली अदालतों के निर्णयों की समीक्षा करने की शक्ति
2. मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए निर्देश जारी करने की शक्ति
3. अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति
4. कुछ मामलों को पहली बार सुनने की शक्ति
(A) P-4, Q-1, R-3, S-2
(B) P-1, Q-4, R-2, S-3
(C) P-4, Q-3, R-1, S-2
(D) P-2, Q-1, R-3, S-4

181. मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान किसी दल के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के कथित करिश्मे से मतदाता की पसंद प्रभावित होना किसका उदाहरण है?
(A) राज्य के चुनावों का राष्ट्रीयकरण।
(B) मतदान व्यवहार का संघीयकरण।
(C) राष्ट्रीय मुद्दों का स्थानीयकरण।
(D) दल के प्रभाव में गिरावट।

182. मध्य प्रदेश का निर्माण 1956 में मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल राज्यों को किस क्षेत्र के हिंदी भाषी क्षेत्रों के साथ मिलाकर किया गया था?
(A) मध्य प्रांत एवं बरार
(B) बॉम्बे राज्य
(C) हैदराबाद राज्य
(D) राजस्थान

183. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संबंध में नीचे दो कथन दिए गए हैं:
कथन I: राज्यपाल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है।
कथन II: मुख्यमंत्री की नियुक्ति में राज्यपाल की पसंद पूर्ण है और किसी भी परंपरा द्वारा निर्देशित नहीं है।
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।

NODIA

208. सूची I (राजनीतिक शब्द) को सूची II (मध्य प्रदेश की राजनीति में प्रासंगिकता) से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
सूची I:
P. द्विध्रुवीयता
Q. पुनर्गठन
R. क्षेत्राधिकार
S. विवेकाधीन शक्ति
सूची II:
1. दलीय व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता
2. उच्च न्यायालय की शक्तियों से संबंधित
3. राज्यपाल के अधिकार का एक पहलू
4. वह प्रक्रिया जिससे 1956 में राज्य बना
(A) P-1, Q-4, R-2, S-3
(B) P-4, Q-1, R-3, S-2
(C) P-1, Q-2, R-4, S-3
(D) P-3, Q-4, R-2, S-1

209. उच्च न्यायालय द्वारा 'अधिकार-पृच्छा' (कूओ वारंटो) की रिट किसके लिए जारी की जा सकती है?
(A) किसी सार्वजनिक पद पर किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच करने के लिए।
(B) निचली अदालत को मामला स्थानांतरित करने के लिए विवश करने के लिए।
(C) निचली अदालत को किसी मामले में कार्यवाही करने से रोकने के लिए।
(D) अवैध रूप से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को रिहा करने का आदेश देने के लिए।

210. ग्रामीण मध्य प्रदेश में मतदान व्यवहार का एक बड़ा निर्धारक अक्सर होता है:
(A) उम्मीदवार का जाति और सामुदायिक संबंध।
(B) राज्य की परमाणु नीति।
(C) अंतर्राष्ट्रीय संधियों पर सरकार का रुख।
(D) भारतीय शेयर बाजार का प्रदर्शन।

211. 2000 में मध्य प्रदेश का विभाजन किसके माध्यम से किया गया था?
(A) एक राष्ट्रपति के आदेश द्वारा
(B) उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय द्वारा
(C) संसद के एक अधिनियम द्वारा
(D) मध्य प्रदेश विधानसभा के एक प्रस्ताव द्वारा

212. मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित और राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक की स्थिति क्या होती है?
(A) यह 6 महीने के बाद स्वतः ही कानून बन जाता है।
(B) राष्ट्रपति का निर्णय (सहमति देना या रोकना) अंतिम होता है।
(C) इसे पुनर्विचार के लिए अध्यक्ष को वापस कर दिया जाता है।
(D) यह स्वतः ही समाप्त हो जाता है।

213. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की योग्यताओं के संबंध में नीचे दो कथन दिए गए हैं:
कथन I: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को हमेशा विधानसभा का सदस्य होना चाहिए।
कथन II: एक व्यक्ति जो विधानसभा का सदस्य नहीं है, उसे छह महीने की अवधि के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है।
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।
(D) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।

214. मध्य प्रदेश विधानसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम किसके द्वारा बनाए जाते हैं?
(A) भारत की संसद
(B) राज्यपाल
(C) स्वयं विधानसभा द्वारा
(D) मुख्यमंत्री कार्यालय

215. निम्नलिखित प्रश्न में, अभिकथन (A) के बाद कारण (R) दिया गया है। सही विकल्प चुनें:
अभिकथन (A): मध्य प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष प्रथम दृष्टया मतदान नहीं करता है।
कारण (R): अध्यक्ष से निष्पक्ष रहने की अपेक्षा की जाती है और वह अपने मत का प्रयोग केवल मत बराबर होने की स्थिति को सुलझाने के लिए करता है।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

NODIA

216. किसी कानून को असंवैधानिक घोषित करने की मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की शक्ति को किस रूप में जाना जाता है?
(A) न्यायिक पुनरावलोकन
(B) न्यायिक सक्रियता
(C) न्यायिक सर्वोच्चता
(D) न्यायिक विवेक

217. मध्य प्रदेश की दलीय व्यवस्था में दो प्रमुख राष्ट्रीय दलों की उपस्थिति और क्या विशेषता है?
(A) कुछ क्षेत्रों में छोटे दलों का महत्वपूर्ण लेकिन सीमित प्रभाव।
(B) किसी अन्य दल की पूर्ण अनुपस्थिति।
(C) प्रत्येक चुनाव में निर्दलीय सदस्यों की निर्णायक भूमिका।
(D) एक क्षेत्रीय दल का वैकल्पिक शासन।

218. राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के कारण राज्यों की निम्नलिखित में से किस श्रेणी को समाप्त कर दिया गया था?

सकती है।
3. राज्य से राज्यसभा सदस्यों के चुनाव में इसकी भूमिका होती है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 3
(D) 1, 2 और 3

243. मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष के निर्णायक मत का उपयोग किसके लिए किया जाता है?
(A) मत बराबर होने की स्थिति को तोड़ने के लिए।
(B) सरकार का समर्थन करने के लिए।
(C) विपक्ष का समर्थन करने के लिए।
(D) व्यक्तिगत राय व्यक्त करने के लिए।

244. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय 'अभिलेख न्यायालय' के रूप में कार्य करता है, जिसका अर्थ है:
(A) इसके निर्णय शाश्वत स्मृति के लिए सुरक्षित रखे जाते हैं और उनका साक्ष्य मूल्य होता है।
(B) यह राज्य विधायिका की सभी कार्यवाहियों को रिकॉर्ड करता है।
(C) यह पूरे राज्य के भूमि रिकॉर्ड का रखरखाव करता है।
(D) यह राज्य सरकार की सभी गतिविधियों का वार्षिक रिकॉर्ड प्रकाशित करता है।

245. मध्य प्रदेश की चुनावी राजनीति में किनके लिए नियमित चुनाव शामिल हैं?
(A) राज्य विधानसभा और लोकसभा।
(B) केवल लोकसभा।
(C) केवल राज्य विधानसभा।
(D) क्षेत्रीय परिषदें।

246. 2000 में मध्य प्रदेश का विभाजन मुख्य रूप से किस आधार पर किया गया था?
(A) प्रशासनिक और विकासात्मक चिंताएं
(B) भाषा
(C) धर्म
(D) जाति

247. मध्य प्रदेश के राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है?
(A) मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
(B) भारत के राष्ट्रपति
(C) निवर्तमान राज्यपाल
(D) मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री

248. मध्य प्रदेश में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है?
(A) मुख्यमंत्री की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा।
(B) मुख्यमंत्री द्वारा।
(C) विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा।
(D) भारत के राष्ट्रपति द्वारा।

249. मध्य प्रदेश विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है?
(A) 25 वर्ष
(B) 21 वर्ष
(C) 30 वर्ष
(D) 35 वर्ष

250. सूची I. (निकाय/व्यक्ति) को सूची II. (मध्य प्रदेश में कार्य) से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

सूची I:
P. राज्यपाल
Q. मुख्यमंत्री
R. अध्यक्ष
S. उच्च न्यायालय

सूची II:
1. वास्तविक कार्यकारी प्राधिकारी
2. संविधान और मौलिक अधिकारों का संरक्षक
3. नाममात्र का कार्यकारी प्राधिकारी
4. सदन की शक्तियों और विशेषाधिकारों का संरक्षक

(A) P-3, Q-1, R-4, S-2
(B) P-1, Q-3, R-4, S-2
(C) P-3, Q-4, R-1, S-2
(D) P-1, Q-2, R-3, S-4

251. विधायिका में विपक्ष के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य है:
(A) जनता को नीतियों का एक वैकल्पिक समूह प्रदान करना।
(B) सरकार को कोई भी कानून पारित करने से रोकना।
(C) सदन की कार्यवाही को निरंतर बाधित करना।
(D) एकता दिखाने के लिए सरकार के सभी निर्णयों का समर्थन करना।

252. उच्च न्यायालय द्वारा 'बंदी प्रत्यक्षीकरण' की रिट जारी करने की शक्ति किसके लिए है?
(A) किसी व्यक्ति की हिरासत की वैधता पर प्रश्न उठाना।
(B) किसी सार्वजनिक प्राधिकरण को अपना कर्तव्य निभाने का आदेश देना।
(C) निचली अदालत के आदेश को रद्द करना।
(D) किसी प्राधिकरण को अपनी शक्तियों से बाहर कार्य करने से रोकना।

253. मध्य प्रदेश की 'राजनीतिक संस्कृति' में क्या शामिल होगा?
(A) राजनीतिक व्यवस्था के प्रति इसके नागरिकों के प्रचलित दृष्टिकोण, विश्वास और मूल्य।
(B) केवल पिछले चुनाव के परिणाम।
(C) भारतीय संविधान का मूल पाठ।
(D) राज्य का भौगोलिक मानचित्र।

Downloaded from www.pdf.tube

(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

231. 2000 से पहले मूल मध्य प्रदेश को अक्सर किस कारण से 'विशाल राज्य' कहा जाता था?
(A) विशाल भौगोलिक क्षेत्र और प्रशासनिक चुनौतियाँ।
(B) अत्यधिक जनसंख्या घनत्व।
(C) अत्यंत उच्च प्रति व्यक्ति आय।
(D) राष्ट्रीय विकास परिषद के स्थायी सदस्य के रूप में दर्जा।

232. मध्य प्रदेश के राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को राज्य विधायिका के पुनः समवेत होने की कितनी अवधि के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए?
(A) छह सप्ताह
(B) छह महीने
(C) एक वर्ष
(D) तीस दिन

233. मध्य प्रदेश में एक मंत्री के 'व्यक्तिगत उत्तरदायित्व' के सिद्धांत का तात्पर्य है कि मंत्री किसके प्रसादपर्यंत पद धारण करता है?
(A) राज्यपाल
(B) विधानसभा
(C) मुख्यमंत्री
(D) राष्ट्रपति

234. मध्य प्रदेश विधानसभा के सामयिक अध्यक्ष (प्रोटेम स्पीकर) की मुख्य भूमिका क्या है?
(A) नवनिर्वाचित सदन की पहली बैठक की अध्यक्षता करना और सदस्यों को शपथ दिलाना।
(B) पूरे पांच साल के कार्यकाल के लिए सदन की कार्यवाही का संचालन करना।
(C) विपक्ष के नेता के रूप में कार्य करना।
(D) सरकार बनाने के बारे में राज्यपाल को सलाह देना।

235. मध्य प्रदेश में राजनीतिक शक्ति पदानुक्रम के सही क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें:
1. मुख्यमंत्री
2. कैबिनेट मंत्री
3. राज्य मंत्री
4. राज्यपाल
(A) 4, 1, 2, 3
(B) 1, 4, 2, 3
(C) 4, 2, 1, 3
(D) 1, 2, 3, 4

236. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसे पत्र लिखकर त्यागपत्र दे सकता है?
(A) भारत के राष्ट्रपति को
(B) मध्य प्रदेश के राज्यपाल को
(C) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को
(D) मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को

237. निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश के चुनावी इतिहास में निरंतर उपस्थिति वाला प्रमुख राजनीतिक दल नहीं है?
(A) भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
(B) भारतीय जनता पार्टी
(C) बहुजन समाज पार्टी
(D) अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस

238. 1956 के पुनर्गठन ने मध्य प्रदेश बनाने के लिए कई रियासतों और क्षेत्रों को एक साथ लाया। इस प्रक्रिया का सबसे अच्छा वर्णन है:
(A) एकीकरण
(B) पृथक्करण
(C) विलय
(D) विखंडन

NODIA

239. निम्नलिखित में से कौन सी मध्य प्रदेश राज्य की एक प्रमुख राजनीतिक विशेषता है?
(A) एकसदनीय विधायिका की परंपरा।
(B) बार-बार और लंबे समय तक राष्ट्रपति शासन लगने का इतिहास।
(C) उच्च मतदाता भागीदारी वाली एक जीवंत राजनीतिक संस्कृति।
(D) इसके गठन के बाद से एक ही दल का प्रभुत्व।

240. मध्य प्रदेश विधानसभा में वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में राज्यपाल का अभिभाषण क्या होता है?
(A) राज्य सरकार की नीति का एक विवरण।
(B) राज्यपाल का व्यक्तिगत भाषण।
(C) विपक्ष की मांगों का सारांश।
(D) न्यायपालिका के प्रदर्शन की समीक्षा।

241. मध्य प्रदेश में कार्यकारी नेतृत्व के संबंध में नीचे दो कथन दिए गए हैं:
कथन I: मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है।
कथन II: राज्यपाल मध्य प्रदेश में कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है।
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
(D) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।

242. मध्य प्रदेश विधानसभा की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह संघ सूची में उल्लिखित सभी विषयों पर कानून बना सकती है।
2. यह सरकार द्वारा प्रस्तुत राज्य के बजट में संशोधन कर

290. 'मतदान व्यवहार' की अवधारणा लोगों के मत देने के तरीके और किसका अध्ययन करती है?
(A) उनके मतदान निर्णय को प्रभावित करने वाले कारक।
(B) मतदान की विधिक प्रक्रियाएं।
(C) मतों की गिनती की प्रक्रिया।
(D) विद्युतीय मतदान यंत्रों का स्वरूप।

291. मध्य प्रदेश के राज्यपाल के पास निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति नहीं है?
(A) कूटनीतिक शक्ति
(B) विधायी शक्ति
(C) कार्यकारी शक्ति
(D) न्यायिक शक्ति

292. मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच का संबंध किसका है?
(A) सलाहकार और राज्य के प्रमुख का।
(B) वरिष्ठ और अधीनस्थ का।
(C) समान भागीदारों का।
(D) राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों का।

293. राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मध्य प्रदेश विधानसभा के कार्यकाल को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है?
(A) संसद
(B) राज्यपाल
(C) राष्ट्रपति
(D) स्वयं राज्य विधायिका

294. सदन में मर्यादा बनाए रखने में अध्यक्ष की भूमिका उनकी किस शक्ति का हिस्सा है?
(A) विनियामक शक्तियां।
(B) न्यायिक शक्तियां।
(C) कार्यकारी शक्तियां।
(D) विधायी शक्तियां।

295. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के संगठन में एक मुख्य न्यायाधीश और कौन शामिल होते हैं?
(A) ऐसे अन्य न्यायाधीश जिन्हें राष्ट्रपति समय-समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझें।
(B) राज्य विधायिका द्वारा निर्धारित अन्य न्यायाधीशों की एक निश्चित संख्या।
(C) बार काउंसिल द्वारा नामित दस वरिष्ठ अधिवक्ता।
(D) जनता द्वारा सीधे चुने गए न्यायाधीश।

296. मध्य प्रदेश के मुख्य राजनीतिक दलों की एक प्रमुख विशेषता यह है कि वे हैं:
(A) कार्यकर्ता-आधारित और जन-आधारित संगठन।
(B) अपने दृष्टिकोण में विशेष रूप से क्षेत्रीय।
(C) केवल शहरी मुद्दों पर केंद्रित।
(D) चुनावों में भाग लेने के लिए अनिच्छुक।

297. 1956 में मध्य प्रदेश के गठन को किस व्यापक प्रक्रिया के हिस्से के रूप में देखा जा सकता है?
(A) राष्ट्रीय एकीकरण और राज्य निर्माण।
(B) आर्थिक योजना।
(C) सामाजिक सुधार।
(D) भूमि सुधार।

298. मध्य प्रदेश के 2000 के विभाजन के संबंध में नीचे दो कथन दिए गए हैं:
कथन I: नया राज्य छत्तीसगढ़ बनाने के लिए 2000 में मध्य प्रदेश का विभाजन किया गया था।
कथन II: विभाजन पूरे राज्य में आयोजित जनमत संग्रह पर आधारित था।
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
(D) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।

299. यदि मध्य प्रदेश के राज्यपाल को लगता है कि विधानसभा द्वारा पारित विधेयक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विरुद्ध है, तो वे:
(A) विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकते हैं।
(B) विधेयक को सीधे अस्वीकार कर सकते हैं।
(C) विधेयक में स्वयं संशोधन कर सकते हैं।
(D) विधेयक को अनिश्चित काल के लिए लंबित रख सकते हैं।

300. मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री किसका नेता होता है?
(A) विधानसभा में बहुमत वाले दल या गठबंधन का।
(B) विधानसभा में विपक्ष का।
(C) राज्य नौकरशाही का।
(D) राज्य न्यायपालिका का।

www.nodia.in

Click Here to Buy book on Amazon

254. राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 किस पर आधारित राज्यों की व्यापक मांग का परिणाम था?
(A) भाषा
(B) आर्थिक स्थिति
(C) जाति
(D) धर्म

255. मध्य प्रदेश के राज्यपाल की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति उनकी:
(A) कुछ स्थितियों में विवेकाधीन शक्तियां हैं।
(B) विश्वविद्यालय के कुलपतियों को नियुक्त करने की शक्ति है।
(C) राज्यसभा में सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति है।
(D) राज्य पुलिस की कमान संभालने की शक्ति है।

256. निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है?
(A) राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच मुख्य कड़ी।
(B) बिना किसी वास्तविक शक्ति के केवल एक नाममात्र का पद।
(C) मुख्य सचिव का अधीनस्थ।
(D) राज्य का एक न्यायिक अधिकारी।

257. मध्य प्रदेश विधानसभा में अध्यक्ष के पद के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए:
1. अध्यक्ष का चुनाव विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है।
2. अध्यक्ष को साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है।
3. अध्यक्ष किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) केवल 1 और 3
(B) केवल 2
(C) केवल 1 और 2
(D) 1, 2 और 3

258. विपक्ष सरकार की वित्तीय नीतियों की जांच किसके माध्यम से कर सकता है?
(A) बजट पर बहस और कटौती प्रस्ताव।
(B) प्रश्नकाल।
(C) उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर करके।
(D) विधानसभा सत्र का बहिष्कार करके।

259. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार का अर्थ है कि वह किससे अपील सुन सकता है?
(A) मध्य प्रदेश के भीतर अधीनस्थ न्यायालयों से।
(B) उच्चतम न्यायालय से।
(C) अन्य राज्यों के उच्च न्यायालयों से।
(D) अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरणों से।

260. मध्य प्रदेश में मतदाताओं का मतदान व्यवहार किसके संयोजन से प्रभावित होता है?
(A) दीर्घकालिक दलीय निष्ठा, अल्पकालिक मुद्दे और उम्मीदवार का प्रदर्शन।
(B) केवल राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दे।
(C) केवल चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादे।
(D) अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों की सलाह।

261. 2000 के बाद, मध्य प्रदेश का भूगोल बदल गया, जिससे यह मुख्य रूप से किस क्षेत्र में स्थित राज्य बन गया?
(A) भारत का मध्य उच्च प्रदेश।
(B) हिमालय की तलहटी।
(C) पश्चिमी भारत के तटीय मैदान।
(D) उत्तर-पश्चिमी भारत का मरुस्थलीय क्षेत्र।

262. राज्यपाल को हटाने के संबंध में नीचे दो कथन दिए गए हैं:
कथन I: राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय हटाया जा सकता है।
कथन II: संविधान राज्यपाल को हटाने के लिए विशिष्ट आधार और विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित करता है।
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
(D) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।

263. मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद किसे सहायता और सलाह देने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य हैं?
(A) राज्यपाल
(B) राष्ट्रपति
(C) प्रधानमंत्री
(D) विधानसभा अध्यक्ष

NODIA

264. मध्य प्रदेश विधानसभा की विधायी शक्तियां पूर्ण नहीं हैं और वे किसके प्रावधानों के अधीन हैं?
(A) भारत का संविधान।
(B) राज्य का वार्षिक बजट।
(C) राज्यपाल के निर्देश।
(D) संयुक्त राष्ट्र के संकल्प।

265. निम्नलिखित प्रश्न में, अभिकथन (A) के बाद कारण (R) दिया गया है। सही विकल्प चुनें:
अभिकथन (A): मध्य प्रदेश में दलीय व्यवस्था काफी हद तक द्विध्रुवीय है।
कारण (R): मध्य प्रदेश के मतदाताओं ने लगातार या तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी को निर्णायक जनादेश दिया है, जिससे तीसरे मोर्चों को हाशिए पर धकेल दिया गया है।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।

(A) केंद्र शासित प्रदेश
(B) भाग A, B और C राज्य
(C) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
(D) अनुसूचित क्षेत्र

219. मध्य प्रदेश की राजनीति की प्रमुख विशेषताओं में से एक किसका उच्च महत्व है?
(A) कृषि संबंधी मुद्दे और किसान कल्याण
(B) समुद्री मुद्दे
(C) चीन के साथ सीमा विवाद
(D) अलगाववादी आंदोलन

220. राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों का उपयोग निम्नलिखित में से किस परिदृश्य में किए जाने की सबसे अधिक संभावना है?
(A) जब चुनाव के परिणामस्वरूप त्रिशंकु विधानसभा बनती है।
(B) जब कोई विधेयक सर्वसम्मति से पारित हो जाता है।
(C) जब मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल विस्तार का अनुरोध करते हैं।
(D) जब विधानसभा सत्र में हो और सामान्य रुप से कार्य कर रही हो।

221. मंत्रिपरिषद के प्रमुख के रूप में मुख्यमंत्री की भूमिका में शामिल है:
(A) मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करना।
(B) उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति करना।
(C) विधायिका के सत्र बुलाना।
(D) क्षमादान और सजा कम करना।

222. मध्य प्रदेश में विपक्ष की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. विपक्ष को 'वैकल्पिक सरकार' के रूप में भी जाना जाता है।
2. विपक्ष की मुख्य भूमिका राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रशंसा करना है।
3. विपक्ष सरकार की जांच के लिए प्रश्न और प्रस्ताव जैसे विधायी उपकरणों का उपयोग करता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) केवल 1 और 3
(B) केवल 2
(C) केवल 1 और 2
(D) 1, 2 और 3

223. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र कहाँ तक विस्तृत है?
(A) मध्य प्रदेश का संपूर्ण राज्य।
(B) केवल जबलपुर शहर।
(C) मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़।
(D) भारत का संपूर्ण मध्य क्षेत्र।

224. मध्य प्रदेश के मुख्य राजनीतिक दल मुख्य रूप से किसके माध्यम से सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं?
(A) चुनावी प्रक्रिया।
(B) न्यायिक प्रक्रिया।
(C) नौकरशाही नियुक्तियां।
(D) सार्वजनिक विरोध और प्रदर्शन।

225. 2000 में मध्य प्रदेश का विभाजन राज्य के राजनीतिक इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसके परिणामस्वरूप:
(A) इसकी भौगोलिक, आर्थिक और जनसांख्यिकीय विशेषताओं का पुनर्निर्धारण हुआ।
(B) इसकी राजधानी शहर में बदलाव हुआ।
(C) एक नई राजकीय भाषा को अपनाया गया।
(D) एक दशक के लिए राष्ट्रपति शासन लागू किया गया।

226. यदि मध्य प्रदेश के राज्यपाल त्यागपत्र देते हैं, तो नया राज्यपाल नियुक्त होने तक कार्यभार कौन संभालता है?
(A) मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश।
(B) राज्य के मुख्यमंत्री।
(C) विधानसभा के अध्यक्ष।
(D) भारत के राष्ट्रपति सीधे राज्य का प्रशासन संभालते हैं।

227. मध्य प्रदेश मंत्रिपरिषद का आकार किसके द्वारा तय किया जाता है?
(A) मुख्यमंत्री द्वारा, संवैधानिक सीमाओं के अधीन।
(B) राज्यपाल द्वारा।
(C) विधानसभा अध्यक्ष द्वारा।
(D) एक प्रस्ताव के माध्यम से राज्य विधायिका द्वारा।

228. निम्नलिखित में से कौन सी मध्य प्रदेश विधानसभा की एक प्रमुख शक्ति है?
(A) राज्य का वार्षिक बजट पारित करना।
(B) विदेश नीति का संचालन करना।
(C) राज्यपाल की नियुक्ति करना।
(D) संविधान की व्याख्या करना।

229. मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष का किस पर अंतिम निर्णय होता है?
(A) कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं।
(B) किसी कानून की संवैधानिकता।
(C) मंत्रियों की नियुक्ति।
(D) विधानसभा का विघटन।

230. निम्नलिखित प्रश्न में, अभिकथन (A) के बाद कारण (R) दिया गया है। सही विकल्प चुनें:
अभिकथन (A): मध्य प्रदेश के मतदान व्यवहार में जाति एक महत्वपूर्ण कारक है।
कारण (R): राजनीतिक दल अक्सर राज्य में चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन करते समय जातिगत गणित पर विचार करते हैं।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।

Downloaded from www.pdf.tube

278. मध्य प्रदेश के राज्यपाल किस समुदाय से एक सदस्य को विधानसभा में मनोनीत कर सकते थे, यदि उसका पर्याप्त प्रतिनिधित्व न हो?
(A) आंग्ल-भारतीय
(B) सिख
(C) पारसी
(D) बौद्ध

279. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की शक्ति और भूमिका किस क्षेत्र में सर्वाधिक है?
(A) राज्य प्रशासन और नीति-निर्माण।
(B) विदेश मामले।
(C) उच्च न्यायालय का कामकाज।
(D) संसदीय चुनावों का संचालन।

280. मध्य प्रदेश विधानसभा निम्नलिखित में से किसे छोड़कर अन्य सभी माध्यमों से कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है?
(A) मुख्य सचिव की नियुक्ति करके
(B) प्रश्नकाल और शून्यकाल के माध्यम से
(C) अविश्वास प्रस्तावों के माध्यम से
(D) स्थगन प्रस्तावों के माध्यम से

281. अध्यक्ष की भूमिका किसके कामकाज के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है?
(A) संसदीय लोकतंत्र
(B) राज्यपाल का कार्यालय
(C) न्यायिक प्रणाली
(D) राज्य की नौकरशाही

282. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की अपने अवमान के लिए दंडित करने की शक्ति किसका उदाहरण है?
(A) अभिलेख न्यायालय के रूप में इसकी शक्ति।
(B) अपीलीय क्षेत्राधिकार।
(C) सलाहकार भूमिका।
(D) पर्यवेक्षी कार्य।

283. मध्य प्रदेश के दो मुख्य राजनीतिक दल किसका प्रतिनिधित्व करते हैं?
(A) प्रतिस्पर्धी विचारधाराओं वाले विभिन्न सामाजिक समूहों के व्यापक गठबंधन।
(B) दो अलग-अलग भाषाई समूह।
(C) विशेष रूप से ग्रामीण-शहरी विभाजन।
(D) राज्य के दर्जे के लिए क्षेत्रीय आंदोलन।

284. 1956 के पुनर्गठन का उद्देश्य ऐसे राज्यों का निर्माण करना था जो:
(A) भौगोलिक रूप से सुगठित और भाषाई रूप से समरूप हों।
(B) आर्थिक रूप से समान हों।
(C) सैन्य रूप से मजबूत हों।
(D) सामाजिक रूप से एक समान हों।

285. 2000 के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति का एक निर्धारक किस पर ध्यान केंद्रित करना रहा है?
(A) अविभाजित राज्य की विरासत से अलग अपनी स्वयं की पहचान विकसित करना।
(B) छत्तीसगढ़ के साथ पुनः विलय।
(C) राजधानी को भोपाल से स्थानांतरित करना।
(D) सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली को अपनाना।

286. मध्य प्रदेश में मंत्रिपरिषद के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए:
1. सभी मंत्रियों को विधानसभा का सदस्य होना चाहिए।
2. मंत्रियों के वेतन राज्यपाल द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।
3. मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) केवल 3
(B) केवल 1 और 3
(C) केवल 2 और 3
(D) 1, 2 और 3

287. मध्य प्रदेश विधानसभा में दलबदल के आधार पर किसी सदस्य की अयोग्यता पर निर्णय लेने का अंतिम अधिकार किसके पास है?
(A) अध्यक्ष
(B) राज्यपाल
(C) उच्च न्यायालय
(D) निर्वाचन आयोग

288. सूची I (अवधारणा) को सूची II (विवरण) से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
सूची I:
P. सामूहिक उत्तरदायित्व
Q. विवेकाधीन शक्ति
R. न्यायिक पुनरावलोकन
S. द्विध्रुवीय दलीय व्यवस्था
सूची II:
1. मंत्रिमंडल एक साथ तैरता और डूबता है।
2. कानूनों की जांच करने की उच्च न्यायालय की शक्ति।
3. राज्यपाल की एक विशेष शक्ति।
4. प्रतिस्पर्धा में दो प्रमुख दल।
(A) P-1, Q-3, R-2, S-4
(B) P-3, Q-1, R-4, S-2
(C) P-1, Q-2, R-3, S-4
(D) P-4, Q-3, R-2, S-1

289. विपक्ष की भूमिका यह सुनिश्चित करना है कि सरकार क्या न बने?
(A) निरंकुश
(B) लोकप्रिय
(C) कुशल
(D) पुनः निर्वाचित

NODIA

(D) A गलत है लेकिन R सही है।

266. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद धारण करता है:
(A) 62 वर्ष की आयु तक।
(B) राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत।
(C) राज्यपाल के प्रसादपर्यंत।
(D) सत्तारूढ़ सरकार के कार्यकाल के दौरान।

267. लोकतंत्र में चुनावी राजनीति वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से:
(A) नागरिकों की प्राथमिकताओं को सार्वजनिक नीति में बदला जाता है।
(B) न्यायपालिका की नियुक्ति की जाती है।
(C) नौकरशाही की भर्ती की जाती है।
(D) अंतर्राष्ट्रीय संधियों पर हस्ताक्षर किए जाते हैं।

268. मध्य प्रदेश राज्य अस्तित्व में आया:
(A) 1 नवंबर, 1956 को
(B) 15 अगस्त, 1947 को
(C) 26 जनवरी, 1950 को
(D) 1 नवंबर, 2000 को

269. 2000 में मध्य प्रदेश का विभाजन किसे बढ़ावा देने के लिए किया गया था?
(A) बेहतर प्रशासनिक दक्षता और केंद्रित क्षेत्रीय विकास।
(B) क्षेत्र में एक नई भाषा।
(C) पड़ोसी देशों के साथ सांस्कृतिक आदान-प्रदान।
(D) नए राज्य में सरकार का एक अलग स्वरूप।

270. मध्य प्रदेश जैसी संसदीय प्रणाली में, राज्यपाल _____ का प्रतिनिधित्व करता है जबकि मुख्यमंत्री _____ का प्रतिनिधित्व करता है।
(A) राज्य; सरकार
(B) जनता; राज्य
(C) गरिमा; दक्षता
(D) दल; कैबिनेट

271. मध्य प्रदेश मंत्रिपरिषद के मंत्री व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी हैं?
(A) राज्यपाल
(B) मुख्यमंत्री
(C) विधानसभा
(D) राष्ट्रपति

272. सूची I (कार्य) को सूची II (मध्य प्रदेश में प्राधिकारी) से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:
सूची I:
P. विधानसभा को भंग करना
Q. वार्षिक बजट पारित करना
R. सदन की बैठक स्थगित करना
S. मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना
सूची II:
1. विधानसभा
2. अध्यक्ष
3. राज्यपाल
(A) P-3, Q-1, R-2, S-3
(B) P-1, Q-2, R-3, S-1
(C) P-3, Q-2, R-1, S-3
(D) P-2, Q-1, R-3, S-2

273. विपक्षी दल रचनात्मक भूमिका निभाते हैं:
(A) नीतियों में कमियां बताकर और विकल्प सुझाकर।
(B) हमेशा हर विधेयक का विरोध करके।
(C) बार-बार राज्यपाल के त्यागपत्र की मांग करके।
(D) किसी भी सदन समिति में भाग लेने से मना करके।

274. उच्च न्यायालय की न्यायपालिका की स्वतंत्रता निम्नलिखित में से किस प्रावधान द्वारा सुरक्षित है?
(A) उनके आचरण पर महाभियोग प्रस्ताव को छोड़कर विधायिका में चर्चा नहीं की जा सकती।
(B) उनके वेतन राज्य विधायिका द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।
(C) उन्हें राज्यपाल द्वारा सुगमता से हटाया जा सकता है।
(D) उनकी नियुक्ति एक लघु, निश्चित अवधि के लिए की जाती है।

275. निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाला अन्य की तुलना में कम महत्वपूर्ण कारक रहा है?
(A) राज्य की विदेश व्यापार नीति
(B) नेतृत्व
(C) जाति और समुदाय
(D) विकास और कल्याणकारी योजनाएं

276. 1956 में मध्य प्रदेश का गठन किस दिशा में एक प्रयास था?
(A) भाषा के आधार पर भारत के राजनीतिक मानचित्र को पुनः निर्मित करना।
(B) प्रशासनिक सुगमता के लिए छोटे राज्यों का निर्माण करना।
(C) देश को आर्थिक क्षेत्रों में विभाजित करना।
(D) संघीय ढांचे को समाप्त करना।

277. मध्य प्रदेश की प्रमुख विशेषताओं में से एक है:
(A) महत्वपूर्ण कृषि अर्थव्यवस्था और ग्रामीण जनसंख्या।
(B) सभी जिलों में उच्च स्तर का शहरीकरण।
(C) आधिकारिक भाषाओं के रूप में अंग्रेजी और फ्रेंच के साथ द्विभाषी नीति।
(D) अधिकांश समुदायों में मातृसत्तात्मक सामाजिक संरचना।

Click Here to Buy book on Amazon

उत्तर (व्याख्या सहित)

1. (B) भाषाई समरूपता
1956 में राज्यों का पुनर्गठन मुख्य रूप से भाषाई आधार पर किया गया था। फजल अली आयोग की अनुशंसाओं के पश्चात, भारत सरकार ने भाषाई एकरूपता सुनिश्चित करने हेतु सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया। मध्य प्रदेश का गठन हिंदी भाषी क्षेत्रों को एकीकृत करके किया गया था। इसका उद्देश्य प्रशासनिक सुगमता और सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखना था। यह भारतीय संघीय ढांचे के विकास में महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ।

2. (A) राज्यपाल राज्य का नाममात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है।
भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यपाल की स्थिति राज्य के औपचारिक अथवा नाममात्र के प्रमुख की होती है। वास्तविक कार्यकारी शक्तियाँ मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है और राज्य प्रशासन की निगरानी करता है। वह संवैधानिक तंत्र के सुचारु संचालन को सुनिश्चित करने हेतु उत्तरदायी होता है। अधिकांश कार्यों में उसे मंत्रिपरिषद का परामर्श मानना पड़ता है।

3. (C) विधानसभा के सत्रों की अध्यक्षता करना और व्यवस्था बनाए रखना।
मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष का प्राथमिक दायित्व सदन की कार्यवाही का निष्पक्ष संचालन करना है। वह सत्रों की अध्यक्षता करते हैं और विधायी नियमों के अनुसार व्यवस्था बनाए रखते हैं। अध्यक्ष सदस्यों के विशेषाधिकारों के संरक्षक होते हैं और विधेयकों पर चर्चा तथा मतदान का प्रबंधन करते हैं। सदन के भीतर किसी भी प्रक्रियात्मक विवाद की स्थिति में उनका निर्णय अंतिम होता है। वे विधानसभा की गरिमा सुनिश्चित करते हैं।

4. (D) मूल क्षेत्राधिकार
मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु रिट जारी करने की मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की शक्ति उसके मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती है। संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत, उच्च न्यायालय नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा हेतु सीधे याचिकाएं स्वीकार कर सकता है। इसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश और उत्प्रेषण जैसी महत्वपूर्ण रिट शामिल हैं। यह विशेष अधिकार क्षेत्र उच्च न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालयों की तुलना में व्यापक और प्रभावी न्यायिक शक्तियां प्रदान करता है।

5. (C) A सही है लेकिन R गलत है।
मध्य प्रदेश में दलीय व्यवस्था मुख्य रूप से दो प्रमुख राष्ट्रीय दलों के बीच द्विध्रुवीय प्रतिस्पर्धा द्वारा पहचानी जाती है। यहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही मुख्य मुकाबला होता है। यद्यपि राज्य में छोटे क्षेत्रीय दल उपस्थित हैं, किंतु उनकी उपस्थिति इतनी प्रभावी नहीं रही कि बार-बार त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति उत्पन्न हो। अधिकांश चुनाव परिणामों में किसी एक दल को शासन हेतु स्पष्ट बहुमत प्राप्त होता रहा है।

6. (B) क्षेत्रीय असमानताएं और छत्तीसगढ़ क्षेत्र का विकास।
वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश का विभाजन मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ क्षेत्र के संतुलित विकास और प्रशासनिक सुगमता के उद्देश्य से प्रेरित था। लंबे समय से यह अनुभव किया जा रहा था कि बड़े भौगोलिक आकार के कारण दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों की विकास संबंधी उपेक्षा हो रही है। आर्थिक संसाधनों के उचित प्रबंधन और स्थानीय आकांक्षाओं को पूर्ण करने हेतु पृथक राज्य की मांग की गई थी। इस विभाजन से शासन प्रणाली अधिक विकेंद्रीकृत हुई।

7. (D) मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करना।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास राज्य प्रशासन से संबंधित व्यापक शक्तियां होती हैं, किंतु उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। यह शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास सुरक्षित है, जो मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल के परामर्श से नियुक्तियां करते हैं। मुख्यमंत्री केवल मंत्रियों की नियुक्ति और विभागों के वितरण पर राज्यपाल को परामर्श देते हैं। वे राज्य सरकार के वास्तविक प्रधान और नीति-निर्माण के मुख्य सूत्रधार होते हैं।

8. (A) P-3, Q-1, R-2, S-4
1956 के पुनर्गठन के समय मध्य प्रांत एवं बरार नए राज्य का मुख्य हिस्सा बना। विंध्य प्रदेश एक भाग 'सी' राज्य था जिसका पूर्णतः विलय कर दिया गया। भोपाल एक रियासत थी जो पश्चात में भाग 'सी' राज्य बनी थी। राजस्थान के कोटा जिले के सिरोंज उपखंड को मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में सम्मिलित किया गया था। यह भौगोलिक एकीकरण विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों को एक भाषाई सूत्र में पिरोने की एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया थी।

9. (C) मध्य प्रदेश विधानसभा
संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत मध्य प्रदेश की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका अर्थ है कि सरकार तब तक सत्ता में बनी रह सकती है जब तक उसे सदन के बहुमत का विश्वास प्राप्त है। विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना अनिवार्य होता है। यह संवैधानिक सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि कार्यपालिका अपनी नीतियों हेतु सीधे निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के प्रति जवाबदेह बनी रहे।

Downloaded from www.pdf.tube

10. (A) विपक्ष के पास बहुमत द्वारा पारित किसी भी विधेयक को निषेध (वीटो) करने की शक्ति होती है।
लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष की भूमिका सरकार की नीतियों की आलोचना और रचनात्मक सुझाव देने की होती है, किंतु उसके पास विधेयकों को वीटो करने की शक्ति नहीं होती। वीटो की शक्ति केवल राज्यपाल के पास संवैधानिक सीमाओं के भीतर होती है। विपक्ष विधानसभा में जनता के मुद्दों को उठाता है और सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करता है। बहुमत द्वारा पारित कानूनों को रोकना विधायी नियमों के अनुसार विपक्ष के संवैधानिक अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

11. (D) न्यायिक पुनरावलोकन
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की विधायी और कार्यकारी कार्यों की संवैधानिकता की समीक्षा करने की शक्ति को न्यायिक पुनरावलोकन कहा जाता है। इस शक्ति के माध्यम से न्यायपालिका यह सुनिश्चित करती है कि सरकार द्वारा निर्मित कोई भी कानून या आदेश भारत के संविधान का उल्लंघन न करे। यदि कोई अधिनियम संवैधानिक प्रावधानों के विरुद्ध पाया जाता है, तो न्यायालय उसे शून्य घोषित कर सकता है। यह शक्ति कानून के शासन को बनाए रखने में सहायक होती है।

12. (B) केवल 1 और 3
भारत के संविधान के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वह उनके प्रसादपर्यंत पद धारण करता है। राज्यपाल का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता और राष्ट्रपति उन्हें किसी भी समय पद से विमुक्त कर सकते हैं। इस पद हेतु न्यूनतम आयु 35 वर्ष पूर्ण होना आवश्यक है। राज्यपाल राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं। वे केंद्र और राज्य सरकार के मध्य एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक कड़ी की भूमिका निभाते हैं।

13. (C) फजल अली आयोग
1956 में मध्य प्रदेश के गठन का मुख्य आधार फजल अली आयोग की अनुशंसाएं थीं। इस आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का सुझाव दिया था, जिसके परिणामस्वरूप मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल की रियासतों का विलय कर एक विशाल हिंदी भाषी राज्य निर्मित किया गया। यह आयोग 1953 में गठित किया गया था और इसकी विवरणिका ने भारतीय मानचित्र के पुनर्निर्धारण में निर्णायक भूमिका निभाई। इसने प्रशासनिक सुगमता और सांस्कृतिक एकता पर बल दिया।

14. (D) सरकार का प्रमुख
मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की भूमिका राज्य सरकार के वास्तविक प्रमुख की होती है। जबकि राज्यपाल राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं, मुख्यमंत्री प्रशासन के संचालन और नीति-निर्माण हेतु उत्तरदायी होते हैं। वे मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करते हैं और राज्य की विकास योजनाओं को क्रियान्वित करने में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। मुख्यमंत्री विधायी कार्यों में सदन के नेता के रूप में कार्य करते हैं। उनका पद लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता की आकांक्षाओं का मुख्य प्रतिनिधित्व करता है।

15. (A) 3, 2, 4, 1
मध्य प्रदेश विधानसभा में विधायी प्रक्रिया एक निश्चित क्रम का अनुसरण करती है। सर्वप्रथम विधेयक को सदन में प्रस्तुत या पुरःस्थापित किया जाता है। इसके पश्चात प्रथम वाचन होता है जिसमें विधेयक के सिद्धांतों पर चर्चा की जाती है। विस्तृत अन्वेषण और संशोधनों के बाद तृतीय वाचन और मतदान की प्रक्रिया संपन्न होती है। अंत में, विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल की अनुमति हेतु भेजा जाता है। अनुमति मिलते ही वह अधिनियम बन जाता है।

16. (B) राष्ट्रीय विदेश नीति के मुद्दे
मध्य प्रदेश की चुनावी राजनीति में मतदान व्यवहार मुख्य रूप से स्थानीय और क्षेत्रीय कारकों द्वारा निर्धारित होता है। इसमें जातीय समीकरण, सरकार का प्रदर्शन और राजनीतिक नेतृत्व का प्रभाव अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चूंकि मध्य प्रदेश एक भू-आबद्ध राज्य है, इसलिए राष्ट्रीय विदेश नीति के मुद्दे सामान्य मतदाताओं के निर्णय को प्रभावित करने की न्यूनतम संभावना रखते हैं। मतदाता सामान्यतः बुनियादी सुविधाओं, रोजगार और कृषि से संबंधित समस्याओं को प्राथमिकता देते हैं।

17. (B) भारत का संविधान
मध्य प्रदेश विधानसभा का संगठन, संरचना और कार्यप्रणाली पूर्णतः भारत के संविधान द्वारा परिभाषित है। संविधान का अनुच्छेद 168 प्रत्येक राज्य हेतु एक विधायिका का प्रावधान करता है। इसमें विधानसभा के सदस्यों के निर्वाचन, कार्यकाल और उनकी शक्तियों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। यह निकाय राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने हेतु सर्वोच्च संस्था है। संवैधानिक प्रावधान यह सुनिश्चित करते हैं कि विधायी प्रक्रिया लोकतांत्रिक मूल्यों और विधिक सीमाओं के भीतर संचालित हो।

18. (A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
संविधान के अनुच्छेद 213 के अंतर्गत, राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की विधायी शक्ति प्राप्त है। जब विधानसभा का सत्र क्रियाशील न हो और तत्काल कार्रवाई आवश्यक हो, तो राज्यपाल अध्यादेश प्रख्यापित कर सकते हैं। इस अध्यादेश की विधिक शक्ति और प्रभाव राज्य विधायिका द्वारा पारित अधिनियम के पूर्णतः समान होता है। यद्यपि, इसे विधानसभा के पुनः समवेत होने के छह सप्ताह के भीतर सदन द्वारा अनुमोदित किया जाना अनिवार्य है, अन्यथा यह स्वतः समाप्त हो जाता है।

19. (C) मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000
वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश से पृथक कर छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के माध्यम से किया गया था। भारत की संसद द्वारा पारित इस ऐतिहासिक कानून ने राज्य की सीमाओं को पुनर्निर्धारित किया। इस अधिनियम का उद्देश्य विशाल भौगोलिक क्षेत्रों में प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना और क्षेत्रीय विकास की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूर्ण करना था। इसके परिणामस्वरूप मध्य प्रदेश के दक्षिण-पूर्वी जिलों को पृथक कर भारत का 26वां राज्य छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आया।

NODIA

20. (C) A सही है लेकिन R गलत है।
संविधान के अनुच्छेद 227 के अनुसार मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय को अपने अधिकार क्षेत्र के समस्त अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की व्यापक शक्ति प्राप्त है। यह शक्ति न्यायपालिका में अनुशासन और एकरूपता बनाए रखने हेतु प्रदान की गई है। यद्यपि, इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि उच्च न्यायालय बिना किसी विधिक आधार के निचली अदालतों के दैनिक और प्रशासनिक कार्यों में सीधा हस्तक्षेप कर सकता है। यह शक्ति केवल न्यायिक और प्रशासनिक निगरानी के माध्यम से न्याय सुनिश्चित करने हेतु है।

21. (C) विधानसभा के कार्यकाल के साथ, जब तक उसे सदन के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता और वह विधानसभा के विश्वास पर निर्भर करता है। सामान्यतः विधानसभा की अवधि पांच वर्ष होती है, किंतु यदि मुख्यमंत्री सदन में बहुमत खो देते हैं, तो उन्हें पद त्यागना पड़ता है। राज्यपाल बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं। यह व्यवस्था संसदीय लोकतंत्र के उत्तरदायित्व के सिद्धांत को सुदृढ़ करती है। जब तक सदन का समर्थन प्राप्त है, मुख्यमंत्री अपने पद पर बने रहते हैं।

22. (B) विधानसभा द्वारा उसके सदस्यों के प्रभावी बहुमत से।
मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष को पद से विमुक्त करने हेतु सदन के सदस्यों के प्रभावी बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करना आवश्यक होता है। इस प्रक्रिया को प्रारंभ करने हेतु न्यूनतम चौदह दिन का पूर्व नोटिस देना अनिवार्य है। अध्यक्ष को हटाने का अधिकार केवल निर्वाचित विधायकों के पास होता है, न कि राज्यपाल या राष्ट्रपति के पास। यह प्रावधान अध्यक्ष की स्वायत्तता और निष्पक्षता को सुरक्षित रखता है। विमुक्ति की प्रक्रिया के दौरान अध्यक्ष सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकते।

23. (D) विशाल आकार और महत्वपूर्ण क्षेत्रीय विविधता।
1956 में गठन के पश्चात से ही मध्य प्रदेश अपनी विशाल भौगोलिक सीमाओं और सांस्कृतिक विविधता हेतु विख्यात रहा है। छत्तीसगढ़ के पृथक होने से पूर्व यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विशालतम राज्य था। इस राज्य में मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड और महाकौशल जैसे विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्र सम्मिलित हैं। यह विविधता राज्य की राजनीति, अर्थव्यवस्था और प्रशासनिक ढांचे को गहराई से प्रभावित करती है। इसकी विशालता के कारण ही इसे भारत का हृदय कहा जाता है।

24. (A) विधानसभा के सत्रों को आहूत करना और सत्रावसान करना।
मध्य प्रदेश के राज्यपाल के पास महत्वपूर्ण विधायी शक्तियाँ होती हैं, जिनमें विधानसभा के सत्र बुलाना और समाप्त करना सम्मिलित है। वे मंत्रिपरिषद के परामर्श पर सदन को संबोधित करते हैं और समय-समय पर संदेश भेजते हैं। राज्यपाल के पास आवश्यकता पड़ने पर विधानसभा को भंग करने का भी अधिकार होता है। ये कार्य राज्य की विधायी प्रक्रिया को औपचारिक रूप से संचालित करने हेतु आवश्यक हैं। जबकि महाधिवक्ता की नियुक्ति उनकी कार्यकारी शक्ति है, सत्र बुलाना विशुद्ध रूप से विधायी कार्य है।

25. (C) दो प्रमुख राष्ट्रीय दलों के बीच।
मध्य प्रदेश की चुनावी राजनीति की मुख्य विशेषता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के मध्य सीधी और तीव्र प्रतिस्पर्धा है। राज्य में दलीय व्यवस्था मुख्य रूप से द्विध्रुवीय रही है, जहाँ सत्ता इन दो प्रमुख राष्ट्रीय दलों के मध्य स्थानांतरित होती रहती है। यद्यपि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी जैसे अन्य दल भी उपस्थित हैं, किंतु उनका प्रभाव कुछ विशिष्ट क्षेत्रों तक ही सीमित है। अधिकांश विधानसभा चुनावों में मुख्य मुकाबला इन्हीं दो बड़े दलों के मध्य ही देखा जाता है।

26. (A) यह मध्य प्रदेश राज्य के भीतर सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण है।
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय राज्य की न्यायपालिका का शिखर संस्थान है और इसके पास व्यापक विधिक शक्तियां हैं। इसकी मुख्य पीठ जबलपुर में स्थित है और इसकी दो अन्य स्थायी खंडपीठ इंदौर तथा ग्वालियर में कार्यरत हैं। उच्च न्यायालय राज्य के समस्त अधीनस्थ न्यायालयों पर प्रशासनिक और न्यायिक नियंत्रण रखता है। यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक है और संविधान की व्याख्या करने का अधिकार रखता है। इसके निर्णय राज्य के भीतर समस्त निचली अदालतों पर बाध्यकारी होते हैं।

27. (D) संपूर्ण मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है।
सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत संसदीय लोकतंत्र की आधारशिला है, जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश की संपूर्ण मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति जवाबदेह होती है। यदि विधानसभा सरकार के किसी भी निर्णय के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करती है, तो मुख्यमंत्री सहित समस्त मंत्रियों को अनिवार्य रूप से त्यागपत्र देना पड़ता है। इसका अर्थ है कि मंत्रिपरिषद एक साथ कार्य करती है और एक साथ उत्तरदायी होती है। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि पूरी सरकार एक इकाई के रूप में सदन के प्रति जवाबदेह रहे।

28. (D) 1, 2 और 3
मध्य प्रदेश विधानसभा के पास व्यापक विधायी और राजनीतिक शक्तियां हैं। यह राज्य सूची के समस्त विषयों पर कानून बनाने का अनन्य अधिकार रखती है। संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत, यह विधान परिषद के सृजन या उत्सादन हेतु संसद को अनुशंसा कर सकती है। इसके अतिरिक्त, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। ये शक्तियाँ राज्य की लोकतांत्रिक व्यवस्था में विधानसभा की केंद्रीय और निर्णायक भूमिका को स्पष्ट रूप से रेखांकित करती हैं।

29. (C) भोपाल
1956 में आधुनिक मध्य प्रदेश का निर्माण चार प्रमुख प्रशासनिक इकाइयों के एकीकरण से हुआ था। इसमें पूर्ववर्ती

Click Here to Buy book on Amazon

प्रकार की अव्यवस्था को रोकते हैं। उनका निष्पक्ष आचरण सरकार की स्थिरता और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करता है।

66. (D) एक प्रमुख राज्य-विशिष्ट द्रविड़ दल
मध्य प्रदेश की दलीय व्यवस्था मुख्य रूप से राष्ट्रीय स्तर के दलों के पर केंद्रित रही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने दशकों से राज्य की राजनीति पर अपना वर्चस्व बनाए रखा है। आरंभिक वर्षों में समाजवादी विचारधारा वाले दलों का भी कुछ प्रभाव था, किंतु द्रविड़ राजनीतिक दल जैसे क्षेत्रीय दल केवल दक्षिण भारत तक सीमित हैं और मध्य प्रदेश की राजनीति में उनकी कोई भूमिका नहीं रही है। यहाँ का राजनीतिक विमर्श सदैव राष्ट्रीय मुख्यधारा की विचारधाराओं और क्षेत्रीय विकास के मुद्दों के मध्य ही रहा है।

67. (A) राज्य पुनर्गठन आयोग
1956 में मध्य प्रदेश का गठन राज्य पुनर्गठन आयोग की दूरदर्शी अनुशंसाओं के आधार पर किया गया था। इस आयोग, जिसे फजल अली आयोग के नाम से भी जाना जाता है, ने भाषाई और प्रशासनिक आधार पर राज्यों की सीमाओं को पुनः परिभाषित करने का सुझाव दिया। इसके फलस्वरूप, हिंदी भाषी क्षेत्रों को एकीकृत करने हेतु कई लघु प्रशासनिक इकाइयों का विलय किया गया। इस ऐतिहासिक पुनर्गठन ने आधुनिक मध्य प्रदेश की आधारशिला रखी और भारत के संघीय ढांचे को एक नया और व्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया।

68. (D) 1, 2 और 3
मध्य प्रदेश की भौगोलिक और जनसांख्यिकीय विशेषताएं इसकी राजनीति और अर्थव्यवस्था के मुख्य निर्धारक हैं। यह एक भू-आबद्ध राज्य है, जिसकी कोई समुद्री सीमा नहीं है, जो इसके व्यापारिक मार्गों को प्रभावित करता है। राज्य में अनुसूचित जनजाति की एक विशाल जनसंख्या है, जिससे जनजातीय कल्याण और वन अधिकार राज्य की राजनीति के केंद्र में रहते हैं। नर्मदा नदी, जिसे राज्य की जीवन रेखा कहा जाता है, न केवल सिंचाई और विद्युत प्रदान करती है, अपितु सामाजिक और सांस्कृतिक विमर्श का भी प्रमुख भाग है।

69. (B) महाधिवक्ता
मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता राज्य के सर्वोच्च विधिक अधिकारी होते हैं और उनकी नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 165 के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा की जाती है। वे राज्य सरकार के मुख्य विधिक परामर्शदाता के रूप में कार्य करते हैं और विभिन्न न्यायालयों में सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके पास राज्य विधानसभा की कार्यवाहियों में भाग लेने और संबोधन का अधिकार होता है, यद्यपि वे मतदान नहीं कर सकते। महाधिवक्ता की भूमिका यह सुनिश्चित करना है कि सरकार के समस्त प्रशासनिक और विधायी कार्य कानून के दायरे में हों।

70. (C) अपीलीय क्षेत्राधिकार
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पास अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली समस्त निचली अदालतों के आदेशों और निर्णयों की समीक्षा करने की शक्ति है। इसे अपीलीय क्षेत्राधिकार कहा जाता है, जिसके अंतर्गत दीवानी और आपराधिक दोनों प्रकार के प्रकरणों में अपील सुनी जा सकती है। यदि किसी पक्ष को जिला अदालत या सत्र न्यायालय के निर्णय से असंतोष है, तो वे न्याय हेतु उच्च न्यायालय का द्वार खटखटा सकते हैं। यह शक्ति सुनिश्चित करती है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रदान की गई विधिक व्याख्याएं सही और न्यायसंगत हों।

71. (B) मुद्दा-आधारित मतदान
जब मतदाता किसी उम्मीदवार या दल की जाति और धर्म के स्थान पर उसके द्वारा घोषित विशिष्ट विकास परियोजनाओं, आर्थिक नीतियों या शासन के वचनों से प्रभावित होकर मत देते हैं, तो इसे मुद्दा-आधारित मतदान कहा जाता है। मध्य प्रदेश में बढ़ती साक्षरता और जागरूकता के कारण मतदाता अब सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे वास्तविक प्रदर्शन के मुद्दों को अधिक प्राथमिकता देने लगे हैं। यह प्रवृत्ति लोकतंत्र की परिपक्वता को दर्शाती है, जहाँ निर्वाचन केवल पहचान के आधार पर नहीं अपितु भविष्य के विकास की दृष्टि पर होते हैं।

72. (B) मुख्यमंत्री
मध्य प्रदेश में सरकार के कार्यकारी निर्णयों हेतु मंत्रिपरिषद की बैठकें अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। इन बैठकों की अध्यक्षता मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है, जो सरकार के वास्तविक प्रमुख और मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं। मुख्यमंत्री ही बैठकों की कार्यसूची निर्धारित करते हैं और नीतिगत निर्णयों पर अंतिम सहमति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनकी अनुपस्थिति में, उनके द्वारा नामित कोई वरिष्ठ मंत्री इस दायित्व का निर्वहन करता है। राज्यपाल इन बैठकों में भाग नहीं लेते, किंतु उन्हें निर्णयों की सूचना प्रदान की जाती है।

73. (B) राज्य सूची और समवर्ती सूची
भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, मध्य प्रदेश विधानसभा के पास राज्य सूची और समवर्ती सूची में उल्लिखित विषयों पर कानून बनाने की विधायी शक्ति है। राज्य सूची में पुलिस, कृषि और सार्वजनिक स्वास्थ्य जैसे स्थानीय महत्व के विषय सम्मिलित हैं, जिन पर राज्य का अनन्य अधिकार है। समवर्ती सूची में शिक्षा और वन्यजीव जैसे विषय हैं, जहाँ केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। यह विभाजन राज्य को अपनी क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप स्वायत्तता के साथ शासन करने और विकास नीतियां बनाने का अधिकार देता है।

74. (D) बॉम्बे प्रेसीडेंसी
1956 में मध्य प्रदेश का गठन मुख्य रूप से मध्य भारत, विंध्य प्रदेश, भोपाल और मध्य प्रांत एवं बरार के हिंदी भाषी क्षेत्रों को सम्मिलित कर किया गया था। बॉम्बे प्रेसीडेंसी एक पृथक प्रशासनिक इकाई थी जिसका अधिकांश भाग गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों में सम्मिलित हुआ। यद्यपि मध्य प्रांत के कुछ मराठी भाषी जिले बॉम्बे राज्य में स्थानांतरित किए गए थे, किंतु बॉम्बे प्रेसीडेंसी स्वयं मध्य प्रदेश के गठन का भाग नहीं थी। यह पुनर्गठन भाषाई एकरूपता सुनिश्चित करने हेतु किया गया था ताकि हिंदी भाषी क्षेत्रों को जोड़ा जा सके।

NODIA

का प्रतिनिधित्व करता है। ये समस्त पद मिलकर राज्य की लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली को संतुलित और प्रभावी बनाते हैं।

39. (D) सत्र न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील।
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार उन मामलों तक सीमित है जिन्हें प्रथम बार सीधे इसी न्यायालय में सुना जा सकता है। इसमें मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन, वसीयत, विवाह विच्छेद और निर्वाचन संबंधी विवाद जैसे विषय सम्मिलित हैं। सत्र न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध सुनवाई करना उच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार का हिस्सा है, न कि मूल क्षेत्राधिकार का। अपीलीय शक्ति के अंतर्गत न्यायालय अधीनस्थ अदालतों के निर्णयों की वैधता की जांच करता है। अतः निचली अदालतों की अपीलें मूल कार्यक्षेत्र से बाहर होती हैं।

40. (B) एक द्विध्रुवीय व्यवस्था जिसमें दो प्रमुख दल बारी-बारी से सत्ता में आते हैं।
मध्य प्रदेश की दलीय व्यवस्था स्पष्ट रुप से द्विध्रुवीय प्रकृति की है, जहाँ भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मध्य सत्ता का संतुलन बना रहता है। यहाँ मतदाताओं का रुझान मुख्य रूप से इन्हीं दो बड़े दलों की ओर रहता है, जिससे तृतीय पक्ष हेतु स्थान सीमित हो जाता है। निर्वाचनों में प्रतिस्पर्धा काफी तीव्र होती है और अक्सर एक दल के पश्चात दूसरा दल सत्ता में आता है। यह स्थिरता राज्य की राजनीति में दीर्घकालिक गठबंधन सरकारों की आवश्यकता को कम करती है।

41. (D) सत्ताधारी दल राज्यपाल द्वारा नियुक्ति के लिए एक नेता का चुनाव करता है।
यदि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद आकस्मिक रूप से रिक्त हो जाता है, तो संवैधानिक परंपरा के अनुसार सत्ताधारी दल अपने नए नेता का निर्वाचन करता है। चयनित नेता का नाम राज्यपाल को प्रस्तावित किया जाता है, जो उन्हें नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान प्रशासन की निरंतरता बनाए रखने हेतु राज्यपाल एक अंतरिम व्यवस्था कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि नवनिर्वाचित नेता को विधानसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त हो, ताकि सरकार स्थिर बनी रहे।

42. (B) राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाना।
मध्य प्रदेश विधानसभा की सबसे प्रमुख शक्ति राज्य सूची और समवर्ती सूची में सम्मिलित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। इसमें कृषि, पुलिस, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक विषय सम्मिलित हैं। यद्यपि समवर्ती सूची के मामलों में केंद्रीय कानून को वरीयता मिलती है, किंतु राज्य अपनी आवश्यकताओं के अनुसार नियम बना सकता है। यह विधायी शक्ति राज्य की स्वायत्तता और संघीय ढांचे को सुदृढ़ता प्रदान करती है। विधानसभा इसके माध्यम से राज्य के सामाजिक और आर्थिक विकास को निर्देशित करती है।

43. (A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 ने भारत के राजनीतिक मानचित्र को व्यापक रुप से बदलते हुए 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे। इसी अधिनियम के अंतर्गत मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर, 1956 को हुआ। उस समय अपनी सीमाओं और क्षेत्रफल के विस्तार के कारण मध्य प्रदेश भारत का भौगोलिक दृष्टि से विशालतम राज्य बन गया था। यह स्थिति वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ के पृथक होने तक बनी रही। यह पुनर्गठन प्रशासनिक दक्षता और भाषाई एकता को बढ़ावा देने हेतु किया गया था।

44. (D) बिना किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा या तटरेखा के केंद्रीय स्थिति।
मध्य प्रदेश को "भारत का हृदय" इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह देश के मध्य में स्थित एक भू-आबद्ध राज्य है। इसकी न तो कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और न ही कोई समुद्री तटरेखा। इसकी सीमाएं केवल भारत के अन्य राज्यों से संलग्न हैं, जो इसे सामरिक और प्रशासनिक रुप से अत्यंत महत्वपूर्ण बनाता है। यह केंद्रीय स्थिति विभिन्न संस्कृतियों के मिलन स्थल के रूप में कार्य करती है। इस भौगोलिक विशेषता के कारण राज्य का व्यापार और परिवहन भी देश के आंतरिक भागों पर केंद्रित है।

45. (B) केवल 1 और 2
मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के पास सरकार को जवाबदेह ठहराने हेतु सशक्त उपकरण होते हैं। वह सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाकर सरकार के बहुमत को चुनौती दे सकता है। इसके अतिरिक्त, विपक्ष का नेता लोकायुक्त जैसी महत्वपूर्ण भ्रष्टाचार विरोधी संस्थाओं की नियुक्ति प्रक्रिया का अभिन्न अंग होता है। यद्यपि विपक्ष बजट पर चर्चा और कटौती प्रस्ताव ला सकता है, किंतु उसके पास बजट को प्रस्तुत होने से रोकने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। यह अधिकार केवल मंत्रिपरिषद और राज्यपाल की अनुशंसा के पास होता है।

46. (C) किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना।
मध्य प्रदेश के राज्यपाल सामान्यतः मंत्रिपरिषद के परामर्श पर कार्य करते हैं, किंतु कुछ विशेष परिस्थितियों में वे अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते हैं। उदाहरण हेतु, यदि उन्हें प्रतीत होता है कि विधानसभा द्वारा पारित कोई विधेयक उच्च न्यायालय की शक्तियों को न्यून करता है या राष्ट्रीय हित के विरुद्ध है, तो वे उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु आरक्षित कर सकते हैं। बहुमत दल के नेता की नियुक्ति या धन विधेयक पर सहमति देना अक्सर संवैधानिक परंपराओं और नियमों के अंतर्गत होता है।

47. (A) राज्यपाल के परामर्श से मुख्यमंत्री द्वारा।
मध्य प्रदेश में मंत्रिपरिषद के गठन की वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री के पास होती है। मुख्यमंत्री ही यह निश्चित करते हैं कि किसे मंत्री बनाया जाएगा और उन्हें कौन से विभाग आवंटित किए जाएंगे। यद्यपि, औपचारिक नियुक्तियां राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के परामर्श पर ही की जाती हैं। मंत्रिपरिषद की संरचना राज्य की राजनीतिक आवश्यकताओं और प्रशासनिक दक्षता को दृष्टिगत रखकर तैयार की जाती है। यह प्रक्रिया

Downloaded from www.pdf.tube

मध्य प्रांत एवं बरार, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल की रियासत को सम्मिलित किया गया था। भोपाल उस समय एक पृथक भाग 'सी' राज्य था, जिसे नए मध्य प्रदेश की राजधानी के रूप में चुना गया। इस एकीकरण ने विभिन्न लघु इकाइयों को समाप्त कर एक विशाल हिंदी भाषी राज्य को जन्म दिया। यह प्रक्रिया भाषाई और प्रशासनिक आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का परिणाम थी।

30. (D) कैबिनेट मंत्री का दर्जा रखते हैं और सरकार की शक्ति पर नियंत्रण रखते हैं।
मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण और गरिमामयी होती है। उन्हें कैबिनेट मंत्री के समान दर्जा, वेतन और सुविधाएं प्राप्त होती हैं। उनका मुख्य कार्य सरकार की नीतियों की रचनात्मक आलोचना करना और प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। वे सरकार की शक्तियों पर अंकुश लगाकर लोकतांत्रिक संतुलन बनाए रखते हैं। विपक्ष का नेता एक सशक्त वैकल्पिक नेतृत्व प्रदान करता है और महत्वपूर्ण नियुक्तियों के चयन में भी सम्मिलित होता है।

31. (A) मध्य प्रदेश के राज्यपाल
भारत के संविधान के अनुसार, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ राज्य के राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है। राज्यपाल बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं और फिर शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाता है। इसके पश्चात मुख्यमंत्री के परामर्श पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति और शपथ का कार्य संपन्न होता है। यह एक महत्वपूर्ण संवैधानिक औपचारिकता है जो सरकार को शासन करने का विधिक अधिकार प्रदान करती है।

32. (B) 62 वर्ष
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु संविधान द्वारा 62 वर्ष निर्धारित की गई है। न्यायाधीश अपने पद पर तब तक बने रहते हैं जब तक वे इस आयु सीमा को प्राप्त नहीं कर लेते। यदि वे चाहें तो इससे पूर्व राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंप सकते हैं। उन्हें हटाने हेतु संसद में एक जटिल प्रक्रिया का अनुसरण करना आवश्यक होता है। यह निश्चित कार्यकाल न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने और न्यायाधीशों को निष्पक्ष रूप से कार्य करने हेतु प्रदान किया गया है।

33. (C) इसकी बड़ी आदिवासी जनसंख्या और उससे जुड़ी राजनीति।
मध्य प्रदेश की राजनीति का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और निर्णायक कारक यहाँ की विशाल अनुसूचित जनजाति जनसंख्या है। राज्य में जनजातीय समुदाय की उपस्थिति सामाजिक और चुनावी ढांचे को गहराई से प्रभावित करती है। विधानसभा में इन समुदायों हेतु बड़ी संख्या में सीटें आरक्षित हैं, जिससे राजनीतिक दलों हेतु जनजातीय कल्याण प्रमुख मुद्दा बन जाता है। जल, जंगल और भूमि से संबंधित नीतियां अक्सर राज्य के चुनावी विमर्श का केंद्र होती हैं। यह जनसांख्यिकीय विशेषता मध्य प्रदेश की राजव्यवस्था को विशिष्ट पहचान प्रदान करती हैं।

34. (D) राज्यपाल
मध्य प्रदेश विधानसभा में धन विधेयक प्रस्तुत करने की प्रक्रिया सामान्य विधेयकों से भिन्न और अधिक औपचारिक होती है। किसी भी धन विधेयक को सदन में पुरःस्थापित करने हेतु राज्य के राज्यपाल की पूर्व अनुमति या अनुशंसा लेना संवैधानिक रूप से अनिवार्य है। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि राज्य के राजस्व और व्यय से संबंधित वित्तीय मामलों में कार्यपालिका का पूर्ण नियंत्रण और उत्तरदायित्व बना रहे। राज्यपाल की सहमति के बिना ऐसे विधेयक पर चर्चा या मतदान संभव नहीं होता है।

35. (A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
मध्य प्रदेश के राज्यपाल की भूमिका दोहरी होती है; वे राज्य के संवैधानिक प्रमुख होने के साथ-साथ केंद्र सरकार के प्रतिनिधि भी होते हैं। उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वे नियमित रूप से राज्य की स्थिति का विवरण केंद्र को प्रेषित करते हैं। यदि राज्य का प्रशासन संविधान के अनुसार संचालित नहीं हो रहा हो, तो राज्यपाल का विवरण ही अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाने का मुख्य आधार बनता है। यह व्यवस्था संघीय ढांचे में केंद्र और राज्य के मध्य कड़ी का कार्य करती है।

36. (B) आदिवासी दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्रों के लिए केंद्रित विकास।
मध्य प्रदेश के विभाजन के पीछे सबसे प्रमुख तर्क दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्रों, विशेषकर जनजातीय बहुल इलाकों का त्वरित और केंद्रित विकास था। तत्कालीन विशाल मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ क्षेत्र के संसाधनों का उचित लाभ स्थानीय निवासियों को नहीं मिल पा रहा था। शासन को जनता के समीप ले जाने और विकास की क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने हेतु पृथक राज्य का निर्माण आवश्यक समझा गया। इस कदम का उद्देश्य प्रशासनिक विकेंद्रीकरण के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना था।

37. (C) मध्य प्रदेश विधानसभा
मध्य प्रदेश की मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री तब तक अपने पद पर बने रह सकते हैं जब तक उन्हें राज्य विधानसभा में बहुमत का समर्थन या विश्वास प्राप्त है। संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका का अस्तित्व सीधे तौर पर निचले सदन के विश्वास पर टिका होता है। यदि विधानसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देती है, तो सरकार को तत्काल त्यागपत्र देना पड़ता है। यद्यपि राज्यपाल औपचारिक रूप से नियुक्तियां करते हैं, किंतु वास्तविक शक्ति का स्रोत विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों का बहुमत ही होता है।

38. (B) P-2, Q-1, R-3, S-4
मध्य प्रदेश की विधायी व्यवस्था में प्रत्येक पद की विशिष्ट भूमिका निर्धारित है। अध्यक्ष विधानसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं जो सदन की मर्यादा बनाए रखते हैं। मुख्यमंत्री सरकार के वास्तविक प्रमुख होते हैं और प्रशासन का नेतृत्व करते हैं। राज्यपाल राज्य के औपचारिक या संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं। विपक्ष का नेता सदन में सबसे बड़े विपक्षी दल

NODIA

57. (D) विधायिका के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित हो।
लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका एक प्रहरी के समान होती है जो सरकार की निरंकुशता पर अंकुश लगाती है। विपक्ष का मुख्य कार्य यह सुनिश्चित करना है कि मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद अपने प्रत्येक कार्य और निर्णय हेतु विधानसभा के प्रति जवाबदेह रहें। प्रश्नकाल, चर्चा और विभिन्न प्रस्तावों के माध्यम से विपक्ष सरकार की त्रुटियों को उजागर करता है। यह प्रक्रिया शासन में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को प्रोत्साहित करती है। एक सशक्त विपक्ष के बिना कार्यपालिका पर विधायी नियंत्रण निर्बल हो सकता है।

58. (B) पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पास अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली समस्त निचली अदालतों की निगरानी करने की व्यापक शक्ति है। पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, उच्च न्यायालय किसी भी अधीनस्थ न्यायालय से किसी प्रकरण को अपने पास मंगवा सकता है, विशेषकर तब जब उसमें कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न सम्मिलित हो। यह शक्ति न्यायपालिका में कार्यकुशलता और न्याय की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु प्रदान की गई है। इसके माध्यम से उच्च न्यायालय यह सुनिश्चित करता है कि निचली अदालतें अपनी विधिक सीमाओं में रहकर कार्य करें।

59. (A) वन आवरण और खनिज संसाधन।
वर्ष 2000 में हुए विभाजन के कारण मध्य प्रदेश को अपनी प्राकृतिक संपदा का एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण भाग खोना पड़ा। नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य में अविभाजित मध्य प्रदेश के विशाल वन क्षेत्र और कोयला, लौह अयस्क जैसे प्रचुर खनिज संसाधन चले गए। इस भौगोलिक परिवर्तन ने राज्य की अर्थव्यवस्था और औद्योगिक परिदृश्य को काफी प्रभावित किया। यद्यपि मध्य प्रदेश अब भी कृषि और कुछ खनिजों में समृद्ध है, किंतु संसाधनों का एक विशाल भंडार विभाजन के पश्चात छत्तीसगढ़ के अधिकार क्षेत्र में चला गया।

60. (A) P-2, Q-1, R-2, S-1
मध्य प्रदेश के संवैधानिक पदों पर नियुक्तियों हेतु पृथक-पृथक प्राधिकारी निर्धारित हैं। राज्य के राज्यपाल और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जो उनके संघीय महत्व को प्रदर्शित करता है। वहीं दूसरी ओर, राज्य के मुख्यमंत्री और महाधिवक्ता की नियुक्ति सीधे राज्यपाल द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री बहुमत दल के नेता होते हैं, जबकि महाधिवक्ता राज्य के सर्वोच्च विधिक अधिकारी होते हैं। यह वितरण संघीय ढांचे और राज्य की स्वायत्तता के मध्य एक संतुलित प्रशासनिक व्यवस्था सुनिश्चित करता है।

61. (B) जातिगत समीकरणों और क्षेत्रीय पहचानों (जैसे मालवा, बघेलखंड) का प्रभाव।
मध्य प्रदेश की राजनीति केवल विचारधाराओं पर नहीं, अपितु गहरे सामाजिक और क्षेत्रीय आधारों पर आधारित है। मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, चंबल और महाकौशल जैसे क्षेत्रों की अपनी विशिष्ट राजनीतिक आकांक्षाएं और मुद्दे हैं। इसके साथ ही, उम्मीदवारों के चयन और मतदाताओं की पसंद में जातिगत गणित एक अत्यंत प्रभावशाली भूमिका निभाता है। राजनीतिक दल अक्सर इन क्षेत्रीय और सामाजिक समीकरणों को दृष्टिगत रखकर अपनी रणनीतियां तैयार करते हैं। यह विविधता राज्य के चुनावी परिणामों को एक रोचक और जटिल आयाम प्रदान करती है।

62. (C) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
मध्य प्रदेश विधानसभा में प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र में राज्यपाल का अभिभाषण एक महत्वपूर्ण संवैधानिक परंपरा है। यह अभिभाषण वास्तव में राज्य सरकार की आगामी नीतियों, उपलब्धियों और कार्यक्रमों का एक औपचारिक विवरण होता है। संविधान के अनुसार, यह भाषण व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल द्वारा नहीं, अपितु मंत्रिपरिषद द्वारा तैयार किया जाता है। राज्यपाल केवल सरकार के दृष्टिकोण को सदन के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। यह प्रक्रिया सरकार की विधायी प्राथमिकताओं को सार्वजनिक करने का एक आधिकारिक माध्यम है, जो लोकतांत्रिक पारदर्शिता को बढ़ाता है।

63. (B) विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15 प्रतिशत।
भारतीय संविधान के 91वें संशोधन अधिनियम के अनुसार, किसी भी राज्य में मंत्रिपरिषद का आकार सीमित कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में भी मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती। यह नियम प्रशासनिक मितव्ययिता बनाए रखने और विशाल मंत्रिमंडल के गठन को रोकने हेतु बनाया गया है। यह राजनीतिक दलबदल और मंत्रियों के पदों के दुरुपयोग पर भी अंकुश लगाता है। यह सीमा सुनिश्चित करती है कि कार्यपालिका का आकार संतुलित और कार्यकुशल बना रहे।

64. (A) वार्षिक राज्य बजट को अधिनियमित करना।
मध्य प्रदेश विधानसभा की प्राथमिक शक्तियों में राज्य की वित्तीय व्यवस्था पर पूर्ण नियंत्रण सम्मिलित है। विधानसभा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य वार्षिक बजट को पारित करना है, जिसके बिना सरकार राज्य की संचित निधि से एक भी मुद्रा व्यय नहीं कर सकती। बजट सत्र के दौरान विधायक सरकार की वित्तीय योजनाओं पर चर्चा करते हैं और अनुदान मांगों को स्वीकृति प्रदान करते हैं। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि जनता के धन का उपयोग विधायी अनुमति और पारदर्शिता के साथ हो। यह कार्यपालिका की जवाबदेही का सशक्त माध्यम है।

65. (B) मतदान प्रक्रिया की निगरानी करते हैं और परिणाम घोषित करते हैं।
जब विधानसभा में सरकार के बहुमत को लेकर संदेह होता है, तो 'शक्ति परीक्षण' या विश्वास मत की प्रक्रिया अपनाई जाती है। इस दौरान अध्यक्ष की भूमिका अत्यंत निर्णायक होती है क्योंकि वे संपूर्ण मतदान प्रक्रिया के निष्पक्ष संचालन हेतु उत्तरदायी होते हैं। वे सुनिश्चित करते हैं कि मतदान नियमों के अनुसार हो और परिणाम की आधिकारिक घोषणा करते हैं। अध्यक्ष सदन की गरिमा को बनाए रखते हैं और किसी भी

Click Here to Buy book on Amazon

101. (A) घट गई।
वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश के विभाजन और छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के परिणामस्वरूप, मूल मध्य प्रदेश की विधानसभा सीटों की कुल संख्या में न्यूनता आई। अविभाजित राज्य में विधानसभा की कुल 320 सीटें थीं, जिनमें से 90 सीटें नवगठित छत्तीसगढ़ विधानसभा को आवंटित कर दी गईं। इसके पश्चात, मध्य प्रदेश विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या घटकर 230 रह गई। इस परिवर्तन ने राज्य के राजनीतिक और चुनावी भूगोल को स्थायी रूप से परिवर्तित कर दिया, जिससे दोनों राज्यों की अपनी स्वतंत्र विधायी पहचान और प्रशासनिक संरचनाएं स्थापित हुईं।

102. (A) केंद्रीय मंत्रिपरिषद
मध्य प्रदेश के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, किंतु संवैधानिक परंपरा के अनुसार राष्ट्रपति यह कार्य प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली केंद्रीय मंत्रिपरिषद के परामर्श पर ही करते हैं। राज्यपाल केंद्र और राज्य के मध्य एक सेतु की भूमिका निर्वहन करते हैं, इसलिए उनकी नियुक्ति में केंद्र सरकार का दृष्टिकोण प्रमुख होता है। यद्यपि नियुक्ति से पूर्व संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से अनौपचारिक परामर्श करने की एक स्वस्थ परंपरा रही है, किंतु अंतिम निर्णय और अधिकार पूर्णतः केंद्र सरकार और राष्ट्रपति के पास ही सुरक्षित होता है।

103. (A) मुख्यमंत्री मत बराबर होने की स्थिति में विधानसभा में निर्णायक मत डाल सकता है।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री राज्य सरकार के वास्तविक प्रमुख होते हैं और राज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद के मध्य संचार का मुख्य माध्यम बनते हैं। वे राज्यपाल को विधानसभा भंग करने का परामर्श भी दे सकते हैं। यद्यपि, विधानसभा की कार्यवाही के दौरान मत बराबर होने की स्थिति में निर्णायक मत डालने का अधिकार केवल विधानसभा अध्यक्ष के पास होता है, मुख्यमंत्री के पास नहीं। मुख्यमंत्री एक सामान्य सदस्य के रूप में ही अपना मत प्रदान कर सकते हैं। निर्णायक मत की शक्ति सदन की निष्पक्षता बनाए रखने हेतु पीठासीन अधिकारी को प्रदान की गई है।

104. (A) राज्यपाल
मध्य प्रदेश की राज्य विधायिका का गठन राज्यपाल और विधानसभा को सम्मिलित कर होता है। राज्यपाल विधायिका का एक अभिन्न भाग होते हैं क्योंकि उनके हस्ताक्षर के बिना कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता, फिर भी वे विधानसभा के सदस्य नहीं होते। वे किसी भी सदन की बैठकों में भाग नहीं लेते और न ही मतदान करते हैं। मुख्यमंत्री, अध्यक्ष और महाधिवक्ता का सदन के साथ भिन्न संबंध होता है, जिसमें मुख्यमंत्री और अध्यक्ष अनिवार्य रूप से सदन के सदस्य होते हैं। राज्यपाल की यह स्थिति उन्हें विधायी प्रक्रिया में एक सर्वोच्च और स्वतंत्र स्थान प्रदान करती है।

105. (B) सरकार बनाने के लिए खुद को एक व्यवहार्य विकल्प के रूप में प्रस्तुत करना।
राजनीतिक अस्थिरता या त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में, विपक्ष की भूमिका अत्यंत सक्रिय और महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसे समय में विपक्ष का यह उत्तरदायित्व है कि वह एक वैकल्पिक सरकार प्रदान करने की अपनी क्षमता प्रदर्शित करे। यदि सत्ताधारी दल बहुमत खो देता है, तो विपक्ष के नेता को राज्यपाल के समक्ष सरकार निर्माण का दावा प्रस्तुत करने का अधिकार होता है, बशर्ते उनके पास आवश्यक समर्थन हो। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि राज्य में प्रशासनिक शून्यता उत्पन्न न हो और लोकतांत्रिक ढंग से नई सरकार का गठन हो सके।

106. (C) उत्प्रेषण (सर्टियोरारी)
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय 'उत्प्रेषण' रिट का प्रयोग तब करता है जब उसे किसी निचली अदालत या न्यायाधिकरण के आदेश की वैधता की जांच करनी होती है। यदि उच्च न्यायालय को प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया है या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध निर्णय दिया है, तो वह उस आदेश को निरस्त कर सकता है। यह रिट मुख्य रूप से न्यायिक और अर्ध-न्यायिक निकायों के विरुद्ध जारी की जाती है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि न्यायपालिका के निचले स्तरों पर कानून का सम्यक अनुपालन हो।

107. (A) भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी
मध्य प्रदेश की दलीय व्यवस्था को एक उत्कृष्ट प्रतिस्पर्धी दो-दलीय प्रणाली के रूप में जाना जाता है। दशकों से राज्य की सत्ता मुख्य रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के मध्य ही रही है। इन दोनों दलों का संगठनात्मक ढांचा संपूर्ण राज्य में अत्यंत सुदृढ़ है, जिससे अन्य क्षेत्रीय या लघु दलों हेतु चुनावी बढ़त बनाना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। मतदाताओं के पास शासन हेतु दो स्पष्ट विचारधारात्मक विकल्प होते हैं, और अक्सर न्यून मतों के अंतर से सत्ता परिवर्तन देखा जाता है। यह प्रतिस्पर्धा राज्य की राजनीति को जीवंत बनाए रखती है।

NODIA

108. (A) भारत की संसद
राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956, जिसके अंतर्गत आधुनिक मध्य प्रदेश का उदय हुआ, भारत की संसद द्वारा पारित एक महत्वपूर्ण विधायी अधिनियम था। संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद को किसी भी राज्य की सीमाओं को परिवर्तित करने या नए राज्य निर्मित करने का अनन्य अधिकार प्राप्त है। संसद ने फजल अली आयोग के विवरण के आधार पर इस कानून को अधिनियमित किया था ताकि देश के प्रशासनिक मानचित्र को भाषाई आधार पर व्यवस्थित किया जा सके। इस कानून ने न केवल मध्य प्रदेश, अपितु देश के कई अन्य राज्यों की वर्तमान सीमाओं और संरचना को भी निर्धारित किया।

109. (A) राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करना।
मध्य प्रदेश के राज्यपाल के पास कुछ विशेष परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जहाँ वे मंत्रिपरिषद के परामर्श के बिना अपने विवेक से निर्णय ले सकते हैं। इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण शक्ति अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के संबंध में राष्ट्रपति को विवरण भेजना है। यह उनकी विवेकाधीन शक्ति का भाग है क्योंकि वे राज्य के संरक्षक के रूप में केंद्र को निष्पक्ष सूचना देने हेतु उत्तरदायी हैं। अन्य कार्य जैसे महाधिवक्ता की

75. (A) A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
मध्य प्रदेश विधानसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाना एक शक्तिशाली विधायी उपकरण है। संसदीय लोकतंत्र में सरकार की स्थिरता सीधे तौर पर निचले सदन के विश्वास पर निर्भर करती है। यदि बहुमत के समर्थन पर कोई संदेह उत्पन्न होता है, तो विपक्ष यह प्रस्ताव ला सकता है। यदि यह प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो पूरी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि कार्यपालिका अपनी नीतियों और कार्यों हेतु निरंतर निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के प्रति जवाबदेह बनी रहे और उनका विश्वास प्राप्त रखे।

76. (A) आंतरिक उपनिवेशवाद और क्षेत्रीय असंतुलन।
वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ का निर्माण उन राजनीतिक प्रक्रियाओं का परिणाम था जिन्होंने बड़े राज्यों के भीतर क्षेत्रीय विकास की गंभीर असमानताओं को उजागर किया था। छत्तीसगढ़ के समर्थकों का तर्क था कि राज्य के प्राकृतिक संसाधनों का लाभ केवल राजधानी और विकसित क्षेत्रों तक ही सीमित रह गया है, जिसे 'आंतरिक उपनिवेशवाद' कहा गया। इस आंदोलन ने शासन की पहुंच को दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुँचाने और स्थानीय संसाधनों पर स्थानीय लोगों का अधिकार सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया। यह विभाजन संतुलित विकास की मांग पर आधारित था।

77. (A) राज्य विधायिका
संविधान के अनुच्छेद 168 के अनुसार, मध्य प्रदेश के राज्यपाल राज्य विधायिका का एक अभिन्न अंग होते हैं। यद्यपि वे किसी सदन के निर्वाचित सदस्य नहीं होते और न ही बैठकों में भाग लेते हैं, किंतु उनके बिना विधायी प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकती। विधानसभा द्वारा पारित कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक उस पर राज्यपाल के हस्ताक्षर न हो जाएं। इसके अतिरिक्त, वे सत्र बुलाने और संबोधित करने का महत्वपूर्ण कार्य भी करते हैं। राज्यपाल की यह भूमिका विधायी और कार्यकारी शक्तियों के मध्य संवैधानिक संतुलन सुनिश्चित करती है।

78. (C) संपूर्ण मंत्रिपरिषद का
मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रमुख और केंद्र बिंदु होते हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के कारण, यदि मुख्यमंत्री अपने पद से त्यागपत्र देते हैं या उनका निधन हो जाता है, तो पूरी मंत्रिपरिषद का स्वतः ही विघटन हो जाता है। इसका अर्थ है कि समस्त मंत्रियों को भी अपने पद छोड़ने पड़ते हैं। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि सरकार मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक एकीकृत इकाई के रूप में कार्य करे। पद की यह रिक्ति तब तक बनी रहती है जब तक कि राज्यपाल नए मुख्यमंत्री और उनकी नई मंत्रिपरिषद की नियुक्ति नहीं कर देते।

79. (A) रचनात्मक आलोचना करना और सरकार को जवाबदेह ठहराना।
विधानसभा में विपक्ष की प्राथमिक भूमिका सरकार के कामकाज पर दृष्टि रखना और उसकी नीतियों की निष्पक्ष समीक्षा करना है। विपक्ष का कार्य केवल विरोध करना नहीं, अपितु जनता के हितों की रक्षा हेतु सरकार की त्रुटियों को उजागर करना और बेहतर विकल्प प्रस्तुत करना है। प्रश्नकाल और चर्चाओं के माध्यम से विपक्ष यह सुनिश्चित करता है कि कार्यपालिका अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न करे। एक सक्रिय और सशक्त विपक्ष ही लोकतंत्र को जीवंत बनाता है और सरकार को निरंतर अपनी कार्यक्षमता सुधारने हेतु प्रेरित करता रहता है।

80. (A) 4, 3, 2, 1
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को विमुक्त करने की प्रक्रिया अत्यंत औपचारिक और कठिन है। इसकी प्रारंभ संसद के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित निष्कासन प्रस्ताव को अध्यक्ष को सौंपने से होती है। यदि प्रस्ताव स्वीकार हो जाता है, तो आरोपों की जांच हेतु एक न्यायिक समिति निर्मित की जाती है। समिति की पुष्टि के पश्चात, संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होना आवश्यक है। अंत में, संसद की इस अनुशंसा के आधार पर भारत के राष्ट्रपति न्यायाधीश को पद से हटाने का आधिकारिक आदेश जारी करते हैं। यह न्यायिक स्वतंत्रता की रक्षा हेतु है।

NODIA

81. (B) राष्ट्रवाद और रुढ़िवाद
भारतीय जनता पार्टी, जो मध्य प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य का एक प्रमुख स्तंभ है, मुख्य रूप से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की विचारधारा के साथ पहचानी जाती है। इस दल की नीतियां अक्सर राष्ट्रीय अखंडता, पारंपरिक मूल्यों और आर्थिक आत्मनिर्भरता पर बल देती हैं। राज्य में इस विचारधारा ने एक विशाल जनाधार निर्मित किया है, जो सांस्कृतिक पहचान और सुदृढ़ शासन को प्राथमिकता देता है। चुनावी राजनीति में यह दल अक्सर इन सिद्धांतों के माध्यम से मतदाताओं को एकजुट करने का प्रयास करता है, जिससे इसकी एक विशिष्ट राजनीतिक पहचान बनी हुई है।

82. (A) क्षेत्रफल
वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ के गठन से पूर्व, मध्य प्रदेश भौगोलिक विस्तार की दृष्टि से भारत का विशालतम राज्य था। इसकी सीमाएं देश के सात भिन्न राज्यों को स्पर्श करती थीं, जो इसकी विशालता को दर्शाता है। इतने बड़े भू-भाग के कारण इसका प्रशासनिक ढांचा काफी व्यापक था, किंतु साथ ही दूरस्थ क्षेत्रों के प्रबंधन में चुनौतियां भी आती थीं। विभाजन के पश्चात, राजस्थान भारत का विशालतम राज्य बन गया और मध्य प्रदेश द्वितीय स्थान पर आ गया। यह भौगोलिक विशालता ही इसे "भारत का हृदय" कहलाने का गौरव प्रदान करती थी।

83. (C) राज्यपाल
मध्य प्रदेश विधानसभा के सत्रों को बुलाने और उन्हें औपचारिक रूप से समाप्त करने की संवैधानिक शक्ति राज्य के राज्यपाल में निहित है। राज्यपाल मंत्रिपरिषद और विशेषकर मुख्यमंत्री के परामर्श पर यह निर्णय लेते हैं कि सत्र कब प्रारंभ होगा और कब समाप्त होगा। यद्यपि सदन की दैनिक कार्यवाही और बैठकों के स्थगन का अधिकार अध्यक्ष के पास होता है, किंतु सत्र के प्रारंभ और अंत की घोषणा राज्यपाल द्वारा ही की जाती है। यह शक्ति सुनिश्चित करती है कि विधायी प्रक्रिया संवैधानिक

समयसीमा और नियमों के अनुसार सुचारु रूप से संचालित होती रहे।

84. (B) मुख्यमंत्री
मध्य प्रदेश में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या और उनके विभागों का निर्धारण वास्तविक रूप से मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है। यद्यपि संविधान ने मंत्रियों की कुल संख्या को विधानसभा सीटों के 15 प्रतिशत तक सीमित कर दिया है, किंतु इस सीमा के भीतर मंत्रियों का चयन और विभागों का आवंटन पूर्णतः मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। वे अपनी राजनीतिक टीम का गठन प्रशासनिक आवश्यकताओं और क्षेत्रीय संतुलन को दृष्टिगत रखकर करते हैं। राज्यपाल केवल मुख्यमंत्री की अनुशंसा के आधार पर इन नियुक्तियों को औपचारिक रूप से स्वीकृति प्रदान करते हैं।

85. (B) अध्यादेश प्रख्यापित करना
विधानसभा में विपक्ष सरकार की जवाबदेही निश्चित करने हेतु प्रश्नकाल, स्थगन प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव जैसे विभिन्न लोकतांत्रिक साधनों का प्रभावी ढंग से प्रयोग करता है। इन माध्यमों से विपक्ष सरकार को महत्वपूर्ण मुद्दों पर घेरता है और नीतियों की त्रुटियां बताता है। अध्यादेश प्रख्यापित करना एक कार्यकारी शक्ति है जो केवल राज्यपाल के पास होती है, और इसे मंत्रिपरिषद के परामर्श पर ही जारी किया जा सकता है। अतः अध्यादेश जारी करना विपक्ष के कार्यक्षेत्र का भाग नहीं है, अपितु यह सरकार का एक विधायी साधन है जिसका प्रयोग सत्र न होने पर होता है।

86. (C) जबलपुर
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ ऐतिहासिक रूप से जबलपुर नगर में स्थित है। यह नगर राज्य की न्यायिक गतिविधियों का केंद्र माना जाता है। 1956 में राज्य के गठन के समय ही जबलपुर को यह गौरव प्रदान किया गया था, जबकि भोपाल को प्रशासनिक राजधानी बनाया गया। उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ के अतिरिक्त, इंदौर और ग्वालियर में दो अन्य स्थायी खंडपीठ भी कार्यरत हैं, ताकि राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों के नागरिकों को सुलभ और त्वरित न्याय प्राप्त हो सके। जबलपुर स्थित मुख्य पीठ राज्य की संपूर्ण न्यायिक व्यवस्था की निगरानी करती है।

87. (B) राज्य स्तर के नेताओं का करिश्मा और आकर्षण।
मध्य प्रदेश की चुनावी राजनीति में मतदान व्यवहार अक्सर प्रमुख राजनीतिक हस्तियों के व्यक्तित्व और उनके नेतृत्व से गहराई से प्रभावित होता है। मतदाता किसी दल की नीतियों के साथ-साथ मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार या पार्टी के शीर्ष क्षेत्रीय नेता की छवि और लोकप्रियता को भी अत्यधिक महत्व देते हैं। एक प्रभावशाली नेता की उपस्थिति न केवल दल के कार्यकर्ताओं में उत्साह भरती है, अपितु मतदाताओं के विश्वास को भी अर्जित करती है। अक्सर नेतृत्व की यह छवि निर्वाचन के अंतिम परिणाम को निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण और निर्णायक भूमिका निभाती है।

88. (A) प्रमुख भाषाई समूह
1956 में भारत में राज्यों के पुनर्गठन का मूल विचार यह था कि प्रशासनिक सीमाओं को देश की प्रमुख भाषाई और सांस्कृतिक विविधताओं के साथ संयोजित किया जाना चाहिए। इस सिद्धांत के अंतर्गत यह माना गया कि यदि शासन जनता की भाषा में संचालित होगा, तो वह अधिक प्रभावी और लोकतांत्रिक होगा। मध्य प्रदेश का गठन भी इसी प्रक्रिया का भाग था, जिसके अंतर्गत विभिन्न हिंदी भाषी रियासतों और क्षेत्रों को एकत्रित कर एक विशाल राज्य बनाया गया। इस भाषाई एकता ने राज्य के भीतर एक साझा पहचान विकसित करने में सहायता की।

89. (B) केवल 2 और 3
वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश का विभाजन मुख्य रूप से बेहतर स्थानीय शासन और दूरस्थ क्षेत्रों के विकास की आवश्यकता पर आधारित था। इस विभाजन से छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ, जबकि झारखंड का निर्माण बिहार से हुआ था। नए राज्य छत्तीसगढ़ के पास अविभाजित मध्य प्रदेश की खनिज संपदा और सघन वन क्षेत्रों का एक महत्वपूर्ण भाग चला गया, साथ ही जनजातीय जनसंख्या का भी एक विशाल भाग वहाँ स्थानांतरित हुआ। इस परिवर्तन ने मध्य प्रदेश की आर्थिक और जनसांख्यिकीय संरचना को मौलिक रूप से बदल दिया, जिससे विकास प्राथमिकताओं में भी परिवर्तन आया।

90. (B) विवेकाधीन मामलों को छोड़कर, राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करना चाहिए।
मध्य प्रदेश में राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति संसदीय लोकतंत्र के सिद्धांतों पर आधारित है। संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार, राज्यपाल को अपनी शक्तियों का प्रयोग करते समय मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद का परामर्श लेना अनिवार्य है, सिवाय उन परिस्थितियों के जहाँ संविधान उन्हें विवेक से कार्य करने का अधिकार देता है। इसका अर्थ है कि वास्तविक शासन की शक्ति निर्वाचित सरकार के पास होती है और राज्यपाल राज्य के औपचारिक प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि प्रशासन लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार के प्रति उत्तरदायी बना रहे।

91. (B) राज्य योजना बोर्ड
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अपनी प्रशासनिक भूमिका के अतिरिक्त कई महत्वपूर्ण वैधानिक और सलाहकार निकायों का नेतृत्व करते हैं। वे राज्य योजना बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं, जहाँ वे राज्य के समग्र आर्थिक विकास और भविष्य की योजनाओं का मार्गदर्शन करते हैं। इस पद के माध्यम से वे संसाधनों के आवंटन और विकासात्मक प्राथमिकताओं को निर्धारित करने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। जबकि मानवाधिकार आयोग और लोक सेवा आयोग स्वतंत्र निकाय हैं, योजना बोर्ड सीधे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कार्य करता है ताकि सरकार की विकास दृष्टि को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके।

92. (B) किसी भी एक दल या चुनाव पूर्व गठबंधन को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो।
मध्य प्रदेश विधानसभा निर्वाचन के संदर्भ में 'त्रिशंकु विधानसभा' वह स्थिति है जब मतदाताओं ने किसी भी एक राजनीतिक दल

Downloaded from www.pdf.tube

को सरकार निर्माण हेतु आवश्यक स्पष्ट बहुमत का जनादेश न दिया हो। ऐसी स्थिति राजनीतिक अनिश्चितता उत्पन्न करती है, जहाँ सरकार बनाने हेतु विभिन्न दलों के मध्य गठबंधन या निर्दलीय सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। यह राज्यपाल हेतु एक चुनौतीपूर्ण समय होता है क्योंकि उन्हें अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग कर एक स्थिर सरकार के गठन की संभावना अन्वेषित करनी पड़ती है।

93. (A) P-1, Q-1, R-1, S-2
मध्य प्रदेश में संवैधानिक शक्तियों का वितरण राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष के मध्य स्पष्ट रूप से विभाजित है। राज्यपाल के पास अपराधियों को क्षमादान देने, सत्र न होने पर अध्यादेश जारी करने और बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करने जैसी महत्वपूर्ण कार्यकारी और न्यायिक शक्तियां होती हैं। दूसरी ओर, वित्तीय मामलों में विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण है क्योंकि वही किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करने का अधिकार रखते हैं। यह शक्तियों का संतुलन राज्य की लोकतांत्रिक और विधायी व्यवस्था हेतु आवश्यक है।

94. (A) धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक लोकतंत्र
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो मध्य प्रदेश की राजनीति का एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण भाग है, पारंपरिक रूप से धर्मनिरपेक्षता, समावेशी विकास और सामाजिक लोकतंत्र की विचारधारा की समर्थक रही है। यह दल समाज के समस्त वर्गों को साथ लेकर चलने और कल्याणकारी नीतियों के माध्यम से आर्थिक असमानता को न्यून करने पर बल देता है। राज्य में कांग्रेस का जनाधार विभिन्न सामाजिक समूहों और ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तृत है। चुनावी विमर्श में यह दल अक्सर सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के मुद्दों को केंद्र में रखकर अपनी पहचान बनाए रखता है।

95. (B) मराठी भाषी विदर्भ क्षेत्र
1956 में जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ, तो भाषाई पुनर्गठन के सिद्धांत के अंतर्गत पूर्ववर्ती मध्य प्रांत एवं बरार के आठ मराठी भाषी जिलों को बॉम्बे राज्य में स्थानांतरित कर दिया गया। इसके विपरीत, शेष हिंदी भाषी क्षेत्रों, विंध्य प्रदेश, भोपाल और मध्य भारत की रियासतों को सम्मिलित कर वर्तमान मध्य प्रदेश निर्मित किया गया। इसमें राजस्थान के सिरोंज उपखंड को भी सम्मिलित किया गया था। इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य एक पूर्णतः हिंदी भाषी राज्य का निर्माण करना था ताकि भाषाई आधार पर प्रशासनिक सुगमता बनी रहे।

96. (C) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
मध्य प्रदेश के राज्यपाल के पास विधानसभा को भंग करने की महत्वपूर्ण संवैधानिक शक्ति होती है, किंतु इसका प्रयोग वे स्वविवेक से नहीं कर सकते। सामान्य परिस्थितियों में, राज्यपाल विधानसभा को केवल मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के परामर्श पर ही भंग करते हैं। यदि सरकार के पास सदन का स्पष्ट बहुमत है, तो राज्यपाल व्यक्तिगत विवेक के आधार पर विधानसभा भंग नहीं कर सकते। यद्यपि, यदि कोई भी दल सरकार निर्माण की स्थिति में न हो या बहुमत खो चुका हो, तब राज्यपाल अपनी विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं।

NODIA

97. (C) उप मंत्री
मध्य प्रदेश की मंत्रिपरिषद एक स्तरीय संरचना है जिसमें विभिन्न श्रेणियों के मंत्री सम्मिलित होते हैं। इसमें शीर्ष स्तर पर कैबिनेट मंत्री होते हैं जो महत्वपूर्ण विभागों के प्रमुख होते हैं। उनके सहायक के रूप में राज्य मंत्री होते हैं, जिन्हें कभी-कभी स्वतंत्र प्रभार भी प्रदान किया जाता है। तृतीय श्रेणी में उप मंत्री सम्मिलित होते हैं, जिनका कार्य कैबिनेट मंत्रियों या राज्य मंत्रियों को उनके प्रशासनिक और विधायी कार्यों में सहायता प्रदान करना होता है। यह त्रि-स्तरीय संगठन कार्यपालिका के भीतर कार्य विभाजन और प्रशासनिक दक्षता सुनिश्चित करने हेतु निर्मित है।

98. (A) विधायिका के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करना।
मध्य प्रदेश विधानसभा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण संवैधानिक भूमिका 'उत्तरदायी सरकार' के सिद्धांत को क्रियान्वित करना है। इसका मुख्य कार्य यह सुनिश्चित करना है कि मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद अपने प्रत्येक निर्णय और वित्तीय व्यय हेतु निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रति जवाबदेह रहें। प्रश्नकाल, चर्चाओं और विभिन्न संसदीय समितियों के माध्यम से विधानसभा सरकार के कामकाज की निगरानी करती है। यह निरंतर जवाबदेही ही लोकतंत्र की आत्मा है, जो कार्यपालिका को निरंकुश होने से रोकती है और शासन में पारदर्शिता तथा जनता की भागीदारी को प्रोत्साहित करती है।

99. (A) ग्वालियर
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्यालय जबलपुर में स्थित है, किंतु राज्य की विशाल भौगोलिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए न्याय की पहुंच सुलभ बनाने हेतु दो स्थायी खंडपीठों की स्थापना की गई है। ये खंडपीठ इंदौर और ग्वालियर नगरों में स्थित हैं। ग्वालियर खंडपीठ उत्तरी मध्य प्रदेश के जिलों की न्यायिक आवश्यकताओं को पूर्ण करती है, जबकि इंदौर खंडपीठ मालवा और निमाड़ क्षेत्रों के प्रकरणों की सुनवाई करती है। यह विकेंद्रीकृत व्यवस्था सामान्य नागरिकों हेतु विधिक प्रक्रिया को सुलभ बनाती है, जिससे न्याय का प्रभावी वितरण सुनिश्चित होता है।

100. (C) A सही है लेकिन R गलत है।
मध्य प्रदेश में चुनावी राजनीति अब विकास, बुनियादी ढांचे और सुशासन के मुद्दों से गहराई से प्रभावित होने लगी है। मतदाता अक्सर सरकार के विगत प्रदर्शन और भविष्य के वचनों को देखकर अपना मत प्रदान करते हैं। यद्यपि जातिगत पहचान समाज का एक महत्वपूर्ण भाग है, किंतु यह कहना त्रुटिपूर्ण होगा कि मतदाता केवल इसी आधार पर मतदान करते हैं। राज्य में सत्ता विरोधी लहर जैसे कारक अक्सर यह सिद्ध करते हैं कि मतदाता प्रदर्शन न करने वाले दलों को परिवर्तित करने की क्षमता रखते हैं। चुनावी परिणाम जन-आकांक्षाओं के बदलते स्वरूप को प्रदर्शित करते हैं।

सुनिश्चित करती है कि कार्यपालिका का नेतृत्व मुख्यमंत्री के पास रहे और वे अपनी टीम का चयन स्वतंत्र रूप से कर सकें।

48. (D) विधानसभा अध्यक्ष
मध्य प्रदेश विधानसभा में किसी विधेयक के स्वरूप को लेकर विवाद होने पर उसे धन विधेयक घोषित करने का अंतिम अधिकार विधानसभा अध्यक्ष के पास होता है। अध्यक्ष द्वारा दिया गया यह प्रमाणीकरण अंतिम और बाध्यकारी होता है, जिसे किसी भी न्यायालय या स्वयं राज्यपाल द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती। यह शक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि धन विधेयक पारित करने की प्रक्रिया साधारण विधेयकों से भिन्न और त्वरित होती है। अध्यक्ष का यह निर्णय सदन की वित्तीय स्वायत्तता और प्रक्रियात्मक सर्वोच्चता को सुरक्षित रखता है।

49. (B) बड़े राज्य के भीतर कथित उपेक्षा और कम विकास।
वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ के निर्माण का प्राथमिक कारण अविभाजित मध्य प्रदेश के भीतर इस क्षेत्र की आर्थिक और प्रशासनिक उपेक्षा थी। छत्तीसगढ़ क्षेत्र संसाधनों से परिपूर्ण होने के उपरांत भी विकास की दौड़ में पिछड़ रहा था और वहाँ के निवासियों को अनुभव होता था कि भोपाल से शासन करना उनकी स्थानीय समस्याओं को हल करने में प्रभावी नहीं है। केंद्रित विकास और बेहतर स्थानीय शासन की आकांक्षा ने इस पृथक राज्य की मांग को सुदृढ़ किया। यह विभाजन विकासात्मक और प्रशासनिक आधार पर था।

50. (A) 1, 2, 3, 4
निर्वाचन के पश्चात सरकार गठन की प्रक्रिया एक संवैधानिक क्रम में संचालित होती है। सर्वप्रथम राज्यपाल बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं। इसके पश्चात, मुख्यमंत्री के परामर्श पर अन्य मंत्रियों को पद की शपथ दिलाई जाती है। सरकार के पूर्ण गठन के पश्चात, राज्यपाल नवनिर्वाचित विधानसभा का प्रथम सत्र आहूत करते हैं। अंत में, राज्यपाल विधानसभा में अपना उद्घाटन अभिभाषण देते हैं, जिसमें सरकार की भावी योजनाओं और नीतियों का विवरण होता है। यह क्रम संसदीय परंपराओं की आधारशिला है।

51. (D) संसद में निर्धारित प्रक्रिया के बाद भारत के राष्ट्रपति द्वारा।
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से विमुक्त करने की प्रक्रिया अत्यंत जटिल है और इसे न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने हेतु कठिन बनाया गया है। किसी न्यायाधीश को केवल सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर ही हटाया जा सकता है। इसके हेतु संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होना अनिवार्य है। संसद की इस अनुशंसा के पश्चात ही भारत के राष्ट्रपति उन्हें पदमुक्त करने का आदेश जारी कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में राज्य सरकार या राज्यपाल की कोई सीधी भूमिका नहीं होती है।

52. (A) मतदाता किसी विशेष दल या उम्मीदवार को कैसे और क्यों चुनते हैं, इसका प्रतिरूप।
चुनावी राजनीति में 'मतदान व्यवहार' एक व्यापक पद है जो उन सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक कारकों का विश्लेषण करता है जो मतदाताओं के निर्णय को प्रभावित करते हैं। इसमें यह अध्ययन किया जाता है कि जाति, धर्म, विकास के मुद्दे, नेतृत्व का आकर्षण और दलीय विचारधारा किस प्रकार मतदान के प्रतिरूप को आकार देते हैं। मध्य प्रदेश के संदर्भ में, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मतदाताओं की प्राथमिकताओं का भिन्न होना मतदान व्यवहार की विविधता को दर्शाता है। यह विश्लेषण चुनावी रणनीतियों के निर्माण में सहायक होता है।

53. (C) भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन।
1956 में मध्य प्रदेश का गठन भारत की उस व्यापक राष्ट्रव्यापी प्रक्रिया का भाग था, जिसका उद्देश्य भाषाई आधार पर प्रशासनिक सीमाओं को तर्कसंगत बनाना था। फजल अली आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार, हिंदी भाषी क्षेत्रों को एकीकृत करने हेतु मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल की रियासतों का विलय कर एक विशाल राज्य बनाया गया। इस कदम का उद्देश्य सांस्कृतिक समरूपता को प्रोत्साहित करना और शासन को जनता की भाषा के समीप लाना था। यह स्वतंत्र भारत के राजनीतिक मानचित्र को व्यवस्थित करने का ऐतिहासिक प्रयास था।

54. (D) अपने पद से त्यागपत्र देना।
यदि मध्य प्रदेश में सत्तारूढ़ दल विधानसभा में अपना बहुमत खो देता है, तो संसदीय परंपराओं के अनुसार मुख्यमंत्री का यह प्राथमिक संवैधानिक दायित्व है कि वे अपने पद से त्यागपत्र दे दें। बहुमत के बिना सरकार के पास शासन करने का कोई नैतिक या विधिक अधिकार शेष नहीं रहता है। ऐसी स्थिति में राज्यपाल वैकल्पिक सरकार निर्माण की संभावना अन्वेषित करते हैं या विधानसभा भंग करने की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत यह अनिवार्य बनाता है कि मंत्रिपरिषद को सदन का निरंतर विश्वास प्राप्त रहे।

55. (C) A सही है लेकिन R गलत है।
मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष से यह अपेक्षा की जाती है कि वे सदन की कार्यवाही के दौरान पूर्णतः निष्पक्ष रहें और समस्त सदस्यों को समान अवसर प्रदान करें। वे सदन की गरिमा और नियमों के संरक्षक होते हैं। यद्यपि, भारतीय संसदीय परंपरा में अध्यक्ष हेतु अपने मूल राजनीतिक दल से त्यागपत्र देना विधिक रूप से अनिवार्य नहीं है, तथापि वे अपनी सक्रिय राजनीतिक गतिविधियाँ बंद कर देते हैं। उनकी निष्पक्षता उनके आचरण और निर्णयों से परिलक्षित होती है, न कि केवल औपचारिक सदस्यता के त्याग से।

56. (B) भारत के संविधान में संशोधन करना।
मध्य प्रदेश की मंत्रिपरिषद राज्य के प्रशासन और नीति-निर्माण हेतु उत्तरदायी है, जिसमें बजट तैयार करना और राज्यपाल को परामर्श देना सम्मिलित है। यद्यपि, भारत के संविधान में संशोधन करने की शक्ति मंत्रिपरिषद या राज्य विधायिका के पास नहीं है। संविधान संशोधन का अधिकार मुख्य रूप से भारत की संसद के पास सुरक्षित है, यद्यपि कुछ विशेष संशोधनों हेतु राज्यों की सहमति आवश्यक होती है। मंत्रिपरिषद का कार्यक्षेत्र केवल राज्य की कार्यकारी और विधायी शक्तियों तक ही सीमित रहता है, संवैधानिक ढांचे में परिवर्तन तक नहीं।

Click Here to Buy book on Amazon

नियुक्ति या साधारण विधेयकों पर सहमति देना सामान्यतः मुख्यमंत्री के परामर्श या संवैधानिक नियमों द्वारा निर्देशित होते हैं।

110. (D) 1, 2 और 3
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री राज्य की मंत्रिपरिषद के वास्तविक मुखिया होते हैं और उनकी भूमिका अत्यंत व्यापक है। वे राज्यपाल के मुख्य परामर्शदाता के रूप में कार्य करते हैं और सरकार के समस्त महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी उन्हें प्रदान करते हैं। मुख्यमंत्री का यह विशेषाधिकार है कि वे मंत्रियों के मध्य विभागों का वितरण करें और आवश्यकतानुसार उनमें परिवर्तन करें। इसके अतिरिक्त, मंत्रिपरिषद की एकजुटता बनाए रखने हेतु वे राज्यपाल को किसी भी मंत्री को पद से विमुक्त करने की अनुशंसा भी कर सकते हैं। ये समस्त शक्तियाँ उन्हें प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान करती हैं।

111. (A) कार्यवाही संचालित करने के लिए उपस्थित होने हेतु आवश्यक सदस्यों की न्यूनतम संख्या।
'गणपूर्ति' वह अनिवार्य शर्त है जिसके बिना मध्य प्रदेश विधानसभा की कोई भी बैठक विधिक रूप से आयोजित नहीं की जा सकती। संविधान के अनुसार, सदन की कार्यवाही प्रारंभ करने हेतु कुल सदस्य संख्या का न्यूनतम दसवां भाग (1/10) उपस्थित होना आवश्यक है। यदि सदन में इस संख्या से न्यून विधायक उपस्थित हैं, तो अध्यक्ष का यह दायित्व है कि वे सदन की बैठक को स्थगित कर दें या तब तक के लिए निलंबित कर दें जब तक कि आवश्यक गणपूर्ति पूर्ण न हो जाए। यह नियम सुनिश्चित करता है कि विधायी निर्णय पर्याप्त प्रतिनिधित्व के साथ लिए जाएं।

112. (B) जब किसी मामले पर सदन समान रूप से विभाजित हो।
मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष से सदन की कार्यवाही के दौरान पूर्ण निष्पक्षता की अपेक्षा की जाती है, इसलिए वे प्रथम बार में मतदान नहीं करते हैं। यद्यपि, यदि किसी विधेयक या प्रस्ताव पर मतदान के दौरान पक्ष और विपक्ष के मत पूर्णतः समान हो जाते हैं, तो अध्यक्ष को अपना निर्णायक मत डालने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। उनके इस मत का उद्देश्य गतिरोध को समाप्त करना और निर्णय को अंतिम रूप प्रदान करना होता है। यह विशेष शक्ति अध्यक्ष को सदन के भीतर एक अत्यंत महत्वपूर्ण और संतुलनकारी भूमिका प्रदान करती है।

113. (A) 62 वर्ष
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा भारत के संविधान द्वारा 62 वर्ष निर्धारित की गई है। इस आयु तक पहुंचने पर न्यायाधीशों को अनिवार्य रूप से अपना पद त्यागना पड़ता है। सेवानिवृत्ति की यह आयु सुनिश्चित करती है कि न्यायाधीशों के पास पर्याप्त अनुभव हो और वे एक गरिमामयी समय तक न्यायपालिका की सेवा कर सकें। यदि कोई न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु से पूर्व त्यागपत्र देना चाहता है, तो वह राष्ट्रपति को संबोधित अपना पत्र दे सकता है। यह निश्चित कार्यकाल न्यायिक प्रणाली में स्थिरता और निष्पक्षता बनाए रखने हेतु आवश्यक है।

114. (B) चुनाव लड़ना और सरकार बनाना।
'चुनावी राजनीति' का तात्पर्य उस संपूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रिया से है जिसके माध्यम से राजनीतिक दल और उम्मीदवार सत्ता प्राप्ति हेतु जनता का समर्थन मांगते हैं। इसमें चुनाव प्रचार, घोषणापत्र तैयार करना, मतदान और अंततः निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा सरकार का गठन सम्मिलित है। मध्य प्रदेश में चुनावी राजनीति अत्यंत सक्रिय है, जहाँ विभिन्न दल विकास और सामाजिक न्याय के वचनों के साथ चुनाव लड़ते हैं। यह प्रक्रिया जनता को अपना प्रतिनिधि चुनने और शासन की नीतियों को प्रभावित करने का वास्तविक अवसर प्रदान करती है, जो लोकतंत्र की मुख्य पहचान है।

NODIA

115. (A) 4, 1, 3, 2
मध्य प्रदेश के राजनीतिक इतिहास का घटनाक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण है। सर्वप्रथम 1948 में मध्य भारत राज्य का गठन किया गया था। इसके पश्चात 1949 में भोपाल रियासत का भारतीय संघ में विलय हुआ। फिर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के माध्यम से विशाल मध्य प्रदेश अस्तित्व में आया, जिसमें इन समस्त इकाइयों को सम्मिलित किया गया। अंततः, वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम द्वारा छत्तीसगढ़ को पृथक कर एक नया राज्य निर्मित किया गया। यह कालानुक्रमिक विकास राज्य की वर्तमान भौगोलिक और प्रशासनिक सीमाओं के क्रमिक निर्माण को स्पष्ट रूप से दर्शाता है।

116. (B) नर्मदा, ताप्ती और चंबल जैसी कई प्रमुख नदी घाटियाँ।
मध्य प्रदेश की भौगोलिक संरचना में इसकी नदी प्रणालियों का विशेष महत्व है, जो राज्य की अर्थव्यवस्था और राजनीति को गहराई से प्रभावित करती हैं। नर्मदा नदी को राज्य की जीवन रेखा माना जाता है, जो कृषि और जल विद्युत हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। ताप्ती और चंबल नदियाँ भी राज्य के विभिन्न भागों में जल संसाधन और उपजाऊ मैदान प्रदान करती हैं। इन नदियों के जल के उपयोग और प्रबंधन को लेकर अक्सर राजनीतिक चर्चाएं और अंतर-राज्यीय समझौते होते रहते हैं। यह प्रचुर जल संपदा मध्य प्रदेश के कृषि प्रधान स्वरूप का मुख्य आधार है।

117. (A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
भारत के संविधान के अनुच्छेद 361 के अंतर्गत, मध्य प्रदेश के राज्यपाल को उनके पद की गरिमा बनाए रखने हेतु विशेष विधिक संरक्षण और उन्मुक्तियां प्रदान की गई हैं। राज्यपाल अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान किए गए किसी भी कार्य हेतु किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। इसके अतिरिक्त, जब तक वे अपने पद पर आसीन रहते हैं, उनके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी आपराधिक कार्यवाही प्रारंभ नहीं की जा सकती और न ही उन्हें बंदी बनाया जा सकता है। यह संवैधानिक सुरक्षा उन्हें बिना किसी बाह्य दबाव के निष्पक्ष कार्य करने में सहायता प्रदान करती है।

118. (C) मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद
यद्यपि राज्यपाल मध्य प्रदेश के संवैधानिक प्रमुख होते हैं और समस्त सरकारी कार्य उनके नाम से किए जाते हैं, किंतु वास्तविक कार्यकारी शक्तियाँ मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली

रखते हैं। यद्यपि, विधानसभा एक स्थायी निकाय नहीं है; इसका सामान्य कार्यकाल पांच वर्ष होता है, जिसके पश्चात इसे भंग कर दिया जाता है और नए निर्वाचन होते हैं। राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श पर इसे पांच वर्ष से पूर्व भी भंग कर सकते हैं। अतः विधानसभा का निरंतर बने रहना संभव नहीं है और इसका पुनर्गठन प्रत्येक निर्वाचन के पश्चात होता है।

186. (B) एक वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रदान करना और सरकार के कार्यों पर नियंत्रण रखना।
विधानसभा में विपक्ष के नेता की भूमिका लोकतंत्र के 'नियंत्रण और संतुलन' सिद्धांत का एक अनिवार्य भाग है। उनका प्राथमिक कर्तव्य सरकार की नीतियों और कार्यों की सूक्ष्म जांच करना और जहाँ त्रुटि हो, वहां जनता के समक्ष एक सशक्त और व्यवहार्य वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करना है। विपक्ष का नेता सदन में जनता की स्वर बनता है और यह सुनिश्चित करता है कि सरकार अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न करे। उनके माध्यम से ही विधायी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही बनी रहती है। वे न केवल सरकार के आलोचक होते हैं अपितु एक 'प्रतीक्षारत सरकार' का प्रतिनिधित्व भी करते हैं।

187. (A) भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल।
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की प्रक्रिया में संघीय सहयोग और न्यायिक स्वायत्तता का संतुलन परिलक्षित होता है। संविधान के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति इस पद पर नियुक्ति करने से पूर्व भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल के साथ अनिवार्य रूप से परामर्श करते हैं। यह बहु-स्तरीय परामर्श प्रक्रिया यह सुनिश्चित करने हेतु अपनाई जाती है कि उच्च न्यायालय के प्रमुख के पद पर एक योग्य और निष्पक्ष व्यक्ति की नियुक्ति हो। इस प्रक्रिया में राष्ट्रपति मुख्य कार्यकारी प्राधिकारी होते हैं, जबकि मुख्य न्यायाधीश न्यायिक इनपुट और राज्यपाल राज्य का संवैधानिक दृष्टिकोण प्रदान करते हैं।

188. (B) वन अधिकार, भूमि हस्तांतरण और सामुदायिक पहचान से संबंधित मुद्दे।
मध्य प्रदेश के जनजातीय बहुल क्षेत्रों में चुनावी राजनीति का केंद्र वहां के निवासियों के जीवन से संबद्ध बुनियादी और भावनात्मक मुद्दे होते हैं। इन क्षेत्रों के मतदाता जल, जंगल और भूमि पर अपने पारंपरिक अधिकारों के संरक्षण को सर्वाधिक महत्व देते हैं। पेसा अधिनियम का क्रियान्वयन, वनाधिकार पट्टों का वितरण और जनजातीय संस्कृति की पहचान की सुरक्षा अक्सर चुनावी विमर्श के मुख्य बिंदु होते हैं। राजनीतिक दल इन समुदायों का समर्थन प्राप्त करने हेतु अपनी नीतियों और घोषणापत्रों में इन विशेष मुद्दों को प्राथमिकता देते हैं। यह जनसांख्यिकीय कारक राज्य के कई जिलों में चुनावी परिणामों को निर्णायक रूप से प्रभावित करता है।

189. (A) भूगोल, समाज और अर्थव्यवस्था जैसे मूलभूत कारक जो इसके राजनीतिक जीवन को आकार देते हैं।
किसी भी राज्य की राजनीति शून्य में कार्य नहीं करती; उसे कुछ मूलभूत 'निर्धारक' प्रभावित करते हैं। मध्य प्रदेश के संदर्भ में, इसकी भू-आबद्ध भौगोलिक स्थिति, विशाल जनजातीय और ग्रामीण जनसंख्या, तथा कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था इसकी राजव्यवस्था को आकार देने वाले मुख्य तत्व हैं। क्षेत्रीय सांस्कृतिक पहचान जैसे मालवा या बुंदेलखंड और सामाजिक संरचना जैसे जातीय समीकरण भी राजनीतिक दलों की रणनीतियों को निर्धारित करते हैं। ये कारक यह निश्चित करते हैं कि चुनावी मुद्दे क्या होंगे, किस प्रकार के नेतृत्व की स्वीकार्यता होगी और शासन की प्राथमिकताएँ क्या रहेंगी। ये राज्य के राजनीतिक जीवन की वास्तविक आधारशिला हैं।

190. (A) A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
मध्य प्रदेश के राज्यपाल के पास विधानसभा द्वारा पारित किसी विधेयक को अपनी सहमति देने के स्थान पर राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित करने की महत्वपूर्ण संवैधानिक शक्ति है। इस शक्ति का प्रयोग विशेष रुप से तब किया जाता है जब राज्यपाल को प्रतीत हो कि संबंधित विधेयक राज्य उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति या उसकी शक्तियों को निर्बल कर सकता है। इसके अतिरिक्त, यदि कोई विधेयक राष्ट्रीय महत्व का हो, संविधान के प्रतिकूल हो या व्यापक जनहित को हानि पहुँचाता हो, तो उसे राष्ट्रपति को प्रेषित करना राज्यपाल का दायित्व है। यह व्यवस्था संघीय ढांचे में केंद्र और राज्य के मध्य एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करती है।

191. (B) राज्य विधायिका
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्यों के वेतन, भत्ते और अन्य वित्तीय सुविधाओं का निर्धारण करने की अनन्य शक्ति राज्य विधायिका के पास है। समय-समय पर विधानसभा में कानून पारित करके इन राशियों को संशोधित किया जाता है। यह प्रावधान विधायी सर्वोच्चता के सिद्धांत पर आधारित है, जिसके अंतर्गत कार्यपालिका के सदस्यों की वित्तीय व्यवस्था निर्वाचित प्रतिनिधियों की स्वीकृति पर निर्भर करती है। ये समस्त व्यय राज्य की संचित निधि से किए जाते हैं। वेतन निर्धारण की यह शक्ति विधानसभा को सरकार की आर्थिक संरचना पर एक महत्वपूर्ण नियंत्रण प्रदान करती है, जो लोकतांत्रिक पारदर्शिता हेतु आवश्यक है।

192. (A) केवल विधानसभा में।
संसदीय लोकतंत्र के नियमों के अनुसार, सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव केवल उसी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है जो सीधे जनता द्वारा निर्वाचित हो। मध्य प्रदेश में चूंकि एकसदनीय विधायिका है, इसलिए यह प्रस्ताव केवल विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति जवाबदेह होती है, इसलिए उसके अस्तित्व का निर्णय भी इसी सदन के बहुमत पर निर्भर करता है। यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो मुख्यमंत्री और उनकी पूरी मंत्रिपरिषद को पद त्यागना पड़ता है। यह विधायी उपकरण सुनिश्चित करता है कि सरकार सदैव निर्वाचित सदन के विश्वास के साथ ही शासन करे।

193. (B) लोकसभा के अध्यक्ष
मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष की संवैधानिक स्थिति, भूमिका और शक्तियां काफी सीमा तक भारत की संसद के निचले सदन, लोकसभा के अध्यक्ष के समान हैं। जिस प्रकार

Downloaded from www.pdf.tube

STUDYING FROM PDFs?

THINK AGAIN.

If you are studying only from PDFs,
you are wasting valuable time.

Research shows that learning from

PRINTED BOOKS has up to

4× HIGHER RETENTION

than studying from screens.

PRINT BOOK = BETTER MEMORY

PDF = LOWER RETENTION

Those who study from **PRINTED BOOKS**
move **AHEAD.**

Others are left **BEHIND**
in competition.

In competitive exams,
being average is not enough.

STAY ONE STEP AHEAD.

चाहिए। ये समस्त प्रक्रियाएँ सदन के सुचारु और व्यवस्थित संचालन हेतु आवश्यक हैं।

127. (B) राज्यपाल को त्यागपत्र देने के लिए विवश करना।
मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्षी दल की मान्यता प्राप्त भूमिकाओं में सरकार की त्रुटियों को उजागर करना और वैकल्पिक नीतियां प्रस्तुत करना सम्मिलित है। विपक्ष उन मतदाताओं का भी प्रतिनिधित्व करता है जिन्होंने सत्तारूढ़ दल को मत प्रदान नहीं किया, जिससे लोकतंत्र का बहुलवादी स्वरूप बना रहता है। यद्यपि, राज्यपाल को पद त्यागने हेतु विवश करना विपक्ष का कार्य नहीं है, क्योंकि राज्यपाल एक संवैधानिक प्रमुख होते हैं और उनका पद दलीय राजनीति से ऊपर होता है। विपक्ष का मुख्य ध्यान कार्यपालिका की जवाबदेही निश्चित करने पर होता है, न कि संवैधानिक प्रमुख के विरुद्ध अभियान चलाने पर।

128. (B) किसी ऐसे आधिकारिक कर्तव्य का पालन करना जिसे निभाने में वे विफल रहे हों या मना कर दिया हो।
'परमादेश' रिट मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया एक शक्तिशाली विधिक आदेश है। यह रिट तब जारी की जाती है जब कोई सार्वजनिक अधिकारी, निगम या निचली अदालत अपने विधिक कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहती है या उसे करने से निषेध कर देती है। इस आदेश के माध्यम से न्यायालय उस अधिकारी को अपना निर्धारित कार्य करने का निर्देश प्रदान करता है। यह सुनिश्चित करता है कि प्रशासनिक तंत्र सक्रिय रहे और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा हो सके। परमादेश केवल उन कर्तव्यों हेतु जारी किया जा सकता है जो कानूनन अनिवार्य हैं।

129. (A) छत्तीसगढ़ की विशिष्ट सांस्कृतिक और प्रशासनिक पहचान।
वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश का विभाजन छत्तीसगढ़ क्षेत्र के निवासियों की अपनी एक पृथक सांस्कृतिक, भाषाई और प्रशासनिक पहचान की दीर्घकाल से चली आ रही मांग का परिणाम था। छत्तीसगढ़ी संस्कृति और वहां के निवासियों की विशेष भौगोलिक और सामाजिक आवश्यकताएं विशाल मध्य प्रदेश के शासन ढांचे में पूर्णतः समाहित नहीं हो पा रही थीं। निवासियों का विश्वास था कि एक लघु और स्वायत्त राज्य उनकी स्थानीय समस्याओं को अधिक संवेदनशीलता के साथ हल कर सकेगा। इस मांग ने दशकों तक चले आंदोलनों के पश्चात अंततः एक संवैधानिक और विधायी स्वरूप प्राप्त किया।

130. (C) कार्यकारी शक्ति
मध्य प्रदेश के राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना उनकी महत्वपूर्ण कार्यकारी शक्तियों का एक भाग है। संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत, राज्यपाल विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को सरकार बनाने हेतु आमंत्रित करते हैं और उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं। यह शक्ति राज्य के प्रशासन की आधारशिला रखती है क्योंकि मुख्यमंत्री ही संपूर्ण कार्यकारी तंत्र का नेतृत्व करते हैं। यद्यपि राज्यपाल इस कार्य में संवैधानिक परंपराओं और चुनावी जनादेश से आबद्ध होते हैं, किंतु यह उनकी औपचारिक कार्यकारी भूमिका का एक सर्वोच्च और निर्णायक आयाम है।

131. (A) राज्य विधायिका के सदस्य हों।
मध्य प्रदेश में मंत्रिपरिषद के सदस्य बनने हेतु यह एक अनिवार्य संवैधानिक शर्त है कि व्यक्ति राज्य विधानसभा का सदस्य हो। यदि कोई व्यक्ति जो विधायक नहीं है, उसे मंत्री नियुक्त किया जाता है, तो उसे अपनी नियुक्ति की तिथि से छह माह की निरंतर अवधि के भीतर विधानसभा हेतु निर्वाचित होना आवश्यक है। यदि वह इस अवधि में सदस्यता प्राप्त करने में विफल रहता है, तो उसे मंत्री पद त्यागना पड़ता है। यह नियम सुनिश्चित करता है कि कार्यपालिका के सदस्य सीधे तौर पर जनता या उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रति जवाबदेह और सदन का भाग बने रहें।

132. (A) केवल 1 और 2
मध्य प्रदेश की विधायिका एकसदनीय है, जिसका अर्थ है कि यहाँ केवल एक सदन 'विधानसभा' कार्यरत है और कोई विधान परिषद नहीं है। विधानसभा के सदस्य सीधे वयस्क मताधिकार के आधार पर जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। पूर्व में राज्यपाल के पास आंग्ल-भारतीय समुदाय के एक सदस्य को नामांकित करने की शक्ति थी, किंतु 104वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इस प्रावधान को अब समाप्त कर दिया गया है। वर्तमान में सदन के समस्त सदस्य निर्वाचित होते हैं। यह संरचना सुनिश्चित करती है कि राज्य की विधायी शक्ति सीधे जनता के प्रतिनिधियों के पास केंद्रित रहे।

NODIA

133. (A) विधानसभा के सदस्यों द्वारा अपने बीच में से।
मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन एक पूर्णतः आंतरिक और लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। नई विधानसभा के गठन के पश्चात, इसके सदस्य अपने में से ही एक योग्य व्यक्ति को अध्यक्ष के रूप में चुनते हैं। यह निर्वाचन सामान्यतः सदन की प्रथम बैठकों के दौरान होता है। अध्यक्ष किसी भी राजनीतिक दल से हो सकते हैं, किंतु निर्वाचित होने के पश्चात उनसे पूर्णतः निष्पक्ष रहने की अपेक्षा की जाती है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि सदन का पीठासीन अधिकारी स्वयं सदन के विश्वास का प्रतिनिधित्व करे और विधायी कार्यों को बिना किसी बाह्य हस्तक्षेप के संचालित कर सके।

134. (B) राष्ट्रीय दल
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जैसे दल, जो मध्य प्रदेश की राजनीति में सक्रिय हैं, निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल हैं। इनका प्रभाव और संगठन केवल मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं है, अपितु देश के कई अन्य राज्यों और केंद्र में भी है। ये दल राष्ट्रीय नीतियों और विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिन्हें वे राज्य स्तर पर स्थानीय मुद्दों के साथ संयोजित कर प्रस्तुत करते हैं। मध्य प्रदेश में इन राष्ट्रीय दलों की प्रबल उपस्थिति ने यहाँ की राजनीति को सदैव राष्ट्रीय विमर्श की मुख्यधारा से जोड़े रखा है, जिससे क्षेत्रीय दलों का प्रभाव अपेक्षाकृत न्यून रहा है।

135. (A) 1956
आधुनिक मध्य प्रदेश राज्य का औपचारिक गठन 1 नवंबर, 1956 को हुआ था। यह भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की एक देशव्यापी प्रक्रिया का परिणाम था, जिसकी अनुशंसा फजल

अली आयोग ने की थी। इस दिन मध्य भारत, विंध्य प्रदेश, भोपाल और मध्य प्रांत एवं बरार की प्रशासनिक इकाइयों को सम्मिलित कर एक नया और विशाल हिंदी भाषी राज्य निर्मित किया गया। 1956 का यह वर्ष राज्य के राजनीतिक और भौगोलिक इतिहास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु माना जाता है क्योंकि इसी ने राज्य को उसकी प्रथम संगठित पहचान और सीमाएं प्रदान की थीं।

136. (A) मध्य प्रदेश के राज्यपाल
मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा संविधान के अनुच्छेद 165 के प्रावधानों के अंतर्गत की जाती है। राज्यपाल इस पद हेतु ऐसे व्यक्ति का चयन करते हैं जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। महाधिवक्ता का मुख्य कार्य राज्य सरकार को विधिक मामलों पर परामर्श देना और न्यायालयों में सरकार का पक्ष प्रस्तुत करना है। वे राज्यपाल के प्रसादपर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। यह पद राज्य की विधिक व्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सरकार के समस्त कार्यों की विधिक वैधता सुनिश्चित करने में सहायता प्रदान करता है।

137. (C) अंतर-राज्यीय परिषद के प्रमुख।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की भूमिका बहुआयामी है; वे राज्य सरकार के मुखिया होने के साथ-साथ राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष और विधानसभा में सदन के नेता के रूप में भी कार्य करते हैं। वे राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के मध्य संचार का एकमात्र आधिकारिक माध्यम होते हैं। यद्यपि, अंतर-राज्यीय परिषद एक राष्ट्रीय स्तर का निकाय है जिसकी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, न कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा। राज्य के मुख्यमंत्री इस परिषद के सदस्य होते हैं जहाँ वे अपने राज्य के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं और संघीय सहयोग को प्रोत्साहित करते हैं।

138. (A) 5 वर्ष
मध्य प्रदेश विधानसभा का सामान्य कार्यकाल इसके प्रथम सत्र की तिथि से पांच वर्ष निर्धारित किया गया है। प्रत्येक पांच वर्ष की समाप्ति पर विधानसभा स्वतः ही भंग हो जाती है और नई विधानसभा के गठन हेतु आम निर्वाचन कराए जाते हैं। यद्यपि, विशेष परिस्थितियों में जैसे राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर, राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श पर इसे पांच वर्ष से पूर्व भी भंग कर सकते हैं। इसके विपरीत, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद कानून निर्मित कर इसके कार्यकाल को एक वर्ष हेतु बढ़ा भी सकती है। यह अवधि लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व का एक मानक चक्र है।

139. (C) विधानसभा अध्यक्ष
मध्य प्रदेश में चूंकि केवल एक ही सदन, विधानसभा, उपस्थित है, इसलिए यहाँ संयुक्त बैठक की स्थिति सामान्यतः उत्पन्न नहीं होती है। संयुक्त बैठक की अवधारणा उन राज्यों में होती है जहाँ द्विसदनीय विधायिका उपस्थित हो। यदि भविष्य में ऐसी कोई स्थिति आती है या संसदीय परंपराओं का अनुसरण किया जाता है, तो ऐसी बैठकों की अध्यक्षता सदैव विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ही की जाती है। अध्यक्ष को सदन की मर्यादा और प्रक्रिया का सर्वोच्च ज्ञान होता है, जिससे वे विधायी गतिरोधों को दूर करने में सक्षम होते हैं। उनका पद निष्पक्षता और पीठासीन सर्वोच्चता का प्रतीक है।

140. (A) A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार एक अत्यंत महत्वपूर्ण न्यायिक शक्ति है जो न्याय की सम्यक व्यवस्था सुनिश्चित करती है। इसके अंतर्गत, न्यायालय राज्य के विभिन्न जिला अदालतों, सत्र न्यायालयों और विशिष्ट न्यायाधिकरणों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुन सकता है। यह शक्ति दीवानी और आपराधिक दोनों श्रेणियों के प्रकरणों में प्रभावी होती है। यदि किसी नागरिक को प्रतीत होता है कि निचली अदालत ने कानून की त्रुटिपूर्ण व्याख्या की है या साक्ष्यों को सही ढंग से नहीं देखा है, तो वे उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। यह प्रक्रिया न्यायिक त्रुटियों को सुधारने में सहायक होती है।

141. (B) बुनियादी ढांचे, सुशासन और मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं जैसे मुद्दे।
मध्य प्रदेश के शहरी निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं का व्यवहार अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में भिन्न होता है। शहरी मतदाता सामान्यतः विकास के आधुनिक मानदंडों जैसे श्रेष्ठ सड़कें, निरंतर विद्युत आपूर्ति, शुद्ध पेयजल, शिक्षा और रोजगार के अवसरों को अधिक प्राथमिकता देते हैं। वे सरकार के सुशासन के विगत अभिलेख और मध्यम वर्ग हेतु निर्मित नीतियों का गहन विश्लेषण करते हैं। शहरी क्षेत्रों में जातीय पहचान का प्रभाव अपेक्षाकृत न्यून होता है और मतदाता का निर्णय जीवन स्तर में सुधार की संभावनाओं और आर्थिक स्थिरता जैसे प्रगतिशील मुद्दों पर अधिक आधारित होता है।

142. (B) भाषाई आधार
1956 में भारत के राज्यों का पुनर्गठन मुख्य रूप से भाषाई आधार पर किया गया था, जो देश की सांस्कृतिक विविधता को प्रशासनिक ढांचे में समाहित करने का एक प्रयास था। इस विचार के पीछे तर्क यह था कि एक ही भाषा भाषी लोगों को एक प्रशासनिक इकाई में रखने से शासन अधिक सुगम और सहभागी बनेगा। मध्य प्रदेश का गठन भी इसी व्यापक प्रक्रिया का परिणाम था, जिसके अंतर्गत हिंदी भाषी विभिन्न क्षेत्रों और रियासतों को एकीकृत किया गया। इस भाषाई पुनर्गठन ने राज्यों के भीतर सांस्कृतिक गौरव को प्रोत्साहित किया और क्षेत्रीय शासन को जनता की भाषा के समीप लाया।

143. (C) भोपाल
वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश के भौगोलिक विभाजन के पश्चात भी राज्य की राजधानी भोपाल ही बनी रही। भोपाल 1956 में राज्य के गठन के समय से ही मध्य प्रदेश का प्रशासनिक केंद्र रहा है और यहाँ समस्त महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालय, विधानसभा भवन और सचिवालय स्थित हैं। विभाजन के समय, रायपुर को नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी बनाया गया, जबकि मध्य प्रदेश के पुराने प्रशासनिक ढांचे और राजधानी नगर में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। भोपाल अपनी ऐतिहासिक विरासत

Click Here to Buy book on Amazon

और आधुनिक बुनियादी ढांचे के साथ राज्य के राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन का केंद्र बना हुआ है।

144. (C) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
मध्य प्रदेश के राज्यपाल के पास राज्य के कानून के विरुद्ध अपराधों हेतु सिद्धदोष व्यक्तियों के दंड को क्षमा करने, उसे न्यून करने या उसे निलंबित करने की महत्वपूर्ण न्यायिक शक्ति होती है। यद्यपि, राज्यपाल की यह क्षमादान शक्ति पूर्ण या निरंकुश नहीं है। भारत के उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णयों के अनुसार, राज्यपाल द्वारा प्रयुक्त क्षमादान शक्ति न्यायिक समीक्षा के अधीन है। यदि यह पाया जाता है कि शक्ति का प्रयोग मनमाने ढंग से, दुर्भावनापूर्ण या बिना किसी ठोस आधार के किया गया है, तो न्यायालय इसमें हस्तक्षेप कर सकता है और इसे निरस्त भी कर सकता है।

145. (C) विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होना।
मध्य प्रदेश की मंत्रिपरिषद को पद से विमुक्त करने का एकमात्र प्रभावी लोकतांत्रिक मार्ग विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित करना है। सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के अनुसार, सरकार को शासन हेतु सदन के बहुमत का निरंतर समर्थन प्राप्त होना चाहिए। यदि विपक्ष ऐसा प्रस्ताव लाता है और उसे सदन के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो जाता है, तो मुख्यमंत्री और उनकी संपूर्ण मंत्रिपरिषद को अनिवार्य रूप से त्यागपत्र देना पड़ता है। यह शक्ति विधानसभा के पास सुरक्षित है और यह सुनिश्चित करती है कि कार्यपालिका सदैव निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी और जवाबदेह बनी रहे।

146. (A) राज्य का कानून, यदि उसे राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हो गई हो।
समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों कानून निर्मित कर सकते हैं। सामान्यतः यदि राज्य का कानून केंद्रीय कानून के प्रतिकूल है, तो केंद्रीय कानून प्रभावी होता है। यद्यपि, संविधान के अनुच्छेद 254(2) के तहत एक विशेष अपवाद है। यदि मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा निर्मित कोई कानून राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित किया गया था और उस पर राष्ट्रपति ने अपनी सहमति प्रदान कर दी है, तो वह विशिष्ट कानून उस राज्य में केंद्रीय कानून के प्रतिकूल होने के उपरांत भी प्रभावी माना जाएगा। यह व्यवस्था राज्य की विधायी स्वायत्तता और विशेष क्षेत्रीय आवश्यकताओं को सुरक्षा प्रदान करती है।

147. (B) विपक्ष की भूमिका
"छाया मंत्रिमंडल" एक संसदीय अवधारणा है जहाँ विपक्षी दल अपने प्रमुख सदस्यों को सत्तारूढ़ सरकार के विशिष्ट मंत्रालयों या विभागों की निगरानी हेतु नियुक्त करता है। इसका उद्देश्य यह है कि विपक्ष का प्रत्येक "छाया मंत्री" सरकार के संबंधित मंत्री के कार्यों पर सूक्ष्म दृष्टि रखे, नीतियों की आलोचना करे और संकट के समय वैकल्पिक नीति प्रस्तुत करे। यद्यपि यह अवधारणा ब्रिटिश संसद में अधिक औपचारिक है, किंतु मध्य प्रदेश जैसी भारतीय संसदीय प्रणालियों में भी विपक्ष अक्सर इसी आधार पर सरकार की जवाबदेही निश्चित करने और भविष्य के शासन हेतु तत्पर रहने का कार्य करता है।

148. (B) किसी कानून या कार्यकारी आदेश की संवैधानिकता की जांच करना।
न्यायिक पुनरावलोकन उच्च न्यायालय की वह सर्वोच्च शक्ति है जिसके माध्यम से वह राज्य विधायिका द्वारा पारित कानूनों और सरकार द्वारा जारी कार्यकारी आदेशों की वैधता का परीक्षण करता है। यदि कोई अधिनियम भारत के संविधान के किसी प्रावधान या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो न्यायालय उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। यह शक्ति सुनिश्चित करती है कि कोई भी कानून संविधान से श्रेष्ठ न हो और सरकार अपनी सीमाओं में रहकर कार्य करे। न्यायिक पुनरावलोकन कानून के शासन को बनाए रखने और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने का मुख्य स्तंभ है।

149. (A) भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
मध्य प्रदेश की दलीय व्यवस्था ऐतिहासिक रूप से भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्चस्व हेतु विख्यात है। राज्य की राजनीति में ये दो प्रमुख राष्ट्रीय दल मुख्य सहभागी हैं, जिनके मध्य सत्ता का सीधा मुकाबला होता है। यद्यपि अन्य क्षेत्रीय और लघु दल निर्वाचन लड़ते हैं, किंतु सरकार निर्माण हेतु आवश्यक बहुमत और जनमत इन्हीं दो बड़े दलों के पास केंद्रित रहता है। इस द्विध्रुवीय व्यवस्था के कारण राज्य में राजनीतिक स्थिरता बनी रहती है और मतदाताओं के पास दो स्पष्ट और सशक्त विचारधारात्मक विकल्पों के मध्य चयन करने का अवसर होता है।

150. (A) P-2, Q-1, R-2, S-1
मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक और राजनीतिक घटनाक्रम को इन महत्वपूर्ण वर्षों के माध्यम से समझा जा सकता है। 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अधिनियमन के साथ ही मूल मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। इसके ठीक 44 वर्ष पश्चात, वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ, जिसके परिणामस्वरूप छत्तीसगढ़ का एक स्वतंत्र राज्य के रूप में उदय हुआ। ये दोनों वर्ष राज्य की सीमाओं और प्रशासनिक स्वरूप के निर्माण में मील के पत्थर हैं। 1956 ने विभिन्न रियासतों को मिलाकर एक विशाल भाषाई राज्य बनाया, जबकि 2000 ने प्रशासनिक सुगमता हेतु इसे दो भागों में विभाजित किया।

151. (A) अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करते हैं।
मध्य प्रदेश के राज्यपाल का कार्यकाल औपचारिक रूप से उस दिन से प्रारंभ होता है जिस दिन वे अपने पद का कार्यभार ग्रहण करते हैं। संविधान के अनुसार यह कार्यकाल पांच वर्ष की अवधि हेतु होता है। यद्यपि, यह पांच वर्ष की अवधि केवल एक सामान्य दिशा-निर्देश है क्योंकि राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत ही अपना पद धारण करते हैं। इसका अर्थ है कि राष्ट्रपति उन्हें पांच वर्ष पूर्ण होने से पूर्व भी विमुक्त कर सकते हैं या उनका कार्यकाल विस्तारित कर सकते हैं। जब तक नया राज्यपाल पदभार ग्रहण नहीं कर लेता, निवर्तमान राज्यपाल अपने पद पर बने रह सकते हैं।

152. (A) मुख्यमंत्री
मध्य प्रदेश में मंत्रियों के मध्य विभागों का आवंटन और उनके कार्यों का वितरण पूर्णतः मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है।

Downloaded from www.pdf.tube

मुख्यमंत्री ही यह निश्चित करते हैं कि कौन सा मंत्री गृह, वित्त या शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभागों का प्रभार संभालेगा। वे किसी भी समय मंत्रियों के विभागों में परिवर्तन कर सकते हैं या उनसे त्यागपत्र की अपेक्षा कर सकते हैं। राज्यपाल केवल मुख्यमंत्री की लिखित अनुशंसा के आधार पर ही इन नियुक्तियों और विभाग आवंटन को अपनी औपचारिक स्वीकृति प्रदान करते हैं। यह शक्ति मुख्यमंत्री को मंत्रिपरिषद पर पूर्ण नियंत्रण और सरकार को नीतिगत दिशा देने में सहायता करती है।

153. (A) उन्हें छह महीने के भीतर विधानसभा के लिए निर्वाचित होना होगा।
भारतीय संविधान के अनुसार, मध्य प्रदेश में किसी ऐसे व्यक्ति को भी मंत्री नियुक्त किया जा सकता है जो उस समय विधानसभा का सदस्य न हो। यद्यपि, यह एक अस्थायी व्यवस्था है और इसके साथ एक अनिवार्य शर्त संलग्न है। उस व्यक्ति को अपनी नियुक्ति की तिथि से निरंतर छह माह की अवधि के भीतर राज्य विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होना होगा। यदि वह छह माह के भीतर विधायक बनने में विफल रहता है, तो वह स्वतः ही अपना मंत्री पद खो देता है और उसे तत्काल त्यागपत्र देना पड़ता है। यह नियम विधायी उत्तरदायित्व के लोकतांत्रिक सिद्धांत को सुनिश्चित करता है।

154. (C) नई विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पहले तक।
मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष का पद अत्यंत महत्वपूर्ण और निरंतरता वाला होता है। जब विधानसभा भंग होती है, तो सदन के अन्य समस्त सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, किंतु अध्यक्ष तत्काल अपना पद नहीं त्यागते। वे नई विधानसभा के निर्वाचन और उसके गठन तक अपने पद पर बने रहते हैं। उनका कार्यकाल नवनिर्वाचित विधानसभा की प्रथम बैठक के ठीक पूर्व तक चलता है। यह व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि नई विधानसभा के गठन के समय शपथ ग्रहण और नए अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया सुचारु और संवैधानिक रीति से संपन्न हो सके।

155. (A) मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन और किसी अन्य उद्देश्य के लिए।
संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की अत्यंत व्यापक शक्ति प्रदान की गई है। उच्च न्यायालय न केवल नागरिकों के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु, अपितु किसी अन्य विधिक अधिकार के उल्लंघन की स्थिति में भी बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश और प्रतिषेध जैसी रिट जारी कर सकता है। यह शक्ति भारत के उच्चतम न्यायालय के अनुच्छेद 32 के तहत प्राप्त रिट क्षेत्राधिकार से भी अधिक विस्तृत है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों हेतु रिट जारी करता है। यह शक्ति उच्च न्यायालय को राज्य में न्याय का शक्तिशाली संरक्षक बनाती है।

156. (B) सत्ता का नियमित परिवर्तन और मजबूत चुनावी प्रतिस्पर्धा।
मध्य प्रदेश में सक्रिय प्रतिस्पर्धी दो-दलीय व्यवस्था ने राज्य की राजनीति को अत्यंत जीवंत और संतुलित बनाया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के मध्य सीधी और कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण राज्य में सत्ता का हस्तांतरण नियमित रूप से होता रहता है। यह प्रतिस्पर्धा राजनीतिक दलों को निरंतर सजग और जनता के प्रति जवाबदेह बनाए रखती है, क्योंकि उन्हें ज्ञात है कि प्रदर्शन न करने पर मतदाता दूसरे विकल्प को चुन सकते हैं। इस व्यवस्था ने राज्य में एक सुदृढ़ चुनावी संस्कृति विकसित की है जहाँ प्रत्येक मत का महत्व है और शासन में पारदर्शिता बनी रहती है।

157. (B) फजल अली आयोग
राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 का मुख्य आधार फजल अली आयोग की ऐतिहासिक रिपोर्ट थी, जिसे 1953 में गठित किया गया था। इस आयोग ने संपूर्ण भारत में भाषाई और प्रशासनिक आवश्यकताओं का गहन अध्ययन किया और राज्यों की सीमाओं को पुनः निर्धारित करने की अनुशंसा की। आयोग का विश्वास था कि भाषाई समरूपता से शासन अधिक प्रभावी और लोकतांत्रिक बनेगा। इसी विवरण के आधार पर मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल की रियासतों का विलय कर आधुनिक मध्य प्रदेश का गठन किया गया। इस आयोग की अनुशंसाओं ने ही स्वतंत्र भारत के संघीय ढांचे को उसका वर्तमान स्वरूप प्रदान किया।

158. (A) केवल 1 और 3
मध्य प्रदेश के राज्यपाल के पास महत्वपूर्ण विधायी और औपचारिक शक्तियां हैं। वे राज्य विधानसभा द्वारा पारित किसी भी विधेयक को अपनी सहमति दे सकते हैं या उसे राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित कर सकते हैं, विशेषकर यदि वह विधेयक उच्च न्यायालय की शक्तियों को प्रभावित करता हो। इसके अतिरिक्त, राज्यपाल प्रत्येक आम निर्वाचन के पश्चात विधानसभा के प्रथम सत्र और प्रति वर्ष के प्रथम सत्र को अनिवार्य रूप से संबोधित करते हैं। यद्यपि, मृत्युदंड के प्रकरणों में पूर्ण क्षमादान देने की शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास है; राज्यपाल केवल दंड को निलंबित या न्यून कर सकते हैं, उसे पूर्णतः समाप्त नहीं कर सकते।

159. (A) विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव द्वारा।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को पद से हटाने का मुख्य संवैधानिक और लोकतांत्रिक मार्ग विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित करना है। चूंकि मुख्यमंत्री सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के अंतर्गत सदन के प्रति जवाबदेह होते हैं, इसलिए उन्हें सत्ता में बने रहने हेतु सदैव सदन के बहुमत का विश्वास प्राप्त होना चाहिए। यदि विधानसभा का बहुमत उनके विरुद्ध हो जाता है, तो उन्हें अनिवार्य रूप से त्यागपत्र देना पड़ता है। राज्यपाल या अन्य कोई अधिकारी उन्हें तब तक नहीं हटा सकते जब तक उनके पास सदन का स्पष्ट बहुमत है। यह शक्ति पूर्णतः निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथ में निहित है।

160. (C) भारत का संविधान (अनुच्छेद 168-212)।
मध्य प्रदेश विधानसभा का संपूर्ण ढांचा, उसकी शक्तियां, संरचना और कार्यकाल सीधे तौर पर भारत के संविधान के प्रावधानों द्वारा अनुशासित होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्य विधायिकाओं के संगठन, अधिकारियों की नियुक्ति, विधायी प्रक्रिया और सदस्यों के विशेषाधिकारों का विस्तृत विवरण प्रदान किया गया है। यह सुनिश्चित करता है

NODIA

कि राज्य की विधायी प्रणाली संपूर्ण देश में एक समान और लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित हो। विधानसभा द्वारा निर्मित नियम और प्रक्रियाएं भी इन्हीं संवैधानिक सीमाओं के भीतर ही होनी चाहिए। संविधान ही इस संस्था की शक्तियों का एकमात्र स्रोत है।

161. (B) कैबिनेट मंत्री
मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता की भूमिका को आधिकारिक मान्यता प्रदान की गई है और उन्हें राज्य सरकार के एक कैबिनेट मंत्री के समान दर्जा प्रदान किया गया है। इसका अर्थ है कि उन्हें कैबिनेट मंत्री के समान वेतन, भत्ते, सरकारी आवास और अन्य प्रशासनिक सुविधाएं प्राप्त होती हैं। यह दर्जा इसलिए प्रदान किया गया है ताकि विपक्ष का नेता बिना किसी असुविधा के सरकार की नीतियों की समीक्षा कर सके और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में प्रभावी भूमिका निर्वहन कर सके। यह प्रावधान शासन में विपक्ष के महत्व को स्वीकार करता है और एक सशक्त वैकल्पिक नेतृत्व को प्रोत्साहित करता है।

162. (B) भारत की संसद
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने हेतु उनके वेतन, भत्ते और अन्य सेवा शर्तों का निर्धारण भारत की संसद द्वारा कानून बनाकर किया जाता है। यद्यपि इन न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं, किंतु राज्य विधायिका को इनमें कोई परिवर्तन करने या न्यूनता करने की शक्ति नहीं है। यह संवैधानिक व्यवस्था न्यायपालिका को राज्य कार्यपालिका और विधायिका के प्रभाव से मुक्त रखने हेतु की गई है। न्यायाधीशों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना निष्पक्ष और निर्भीक न्याय प्रणाली की स्थापना हेतु अनिवार्य है।

163. (B) सत्तारूढ़ दल या वर्तमान प्रतिनिधि के विरुद्ध एक भावना।
चुनावी राजनीति में "सत्ता-विरोधी लहर" का तात्पर्य मतदाताओं के उस व्यापक असंतोष से है जो वर्तमान सरकार या सत्ताधारी दल के विरुद्ध होता है। यह स्थिति अक्सर तब उत्पन्न होती है जब जनता सरकार के प्रदर्शन, भ्रष्टाचार या बुनियादी सुविधाओं की न्यूनता से निराश होती है और परिवर्तन चाहती है। मध्य प्रदेश में भी कई बार निर्वाचन परिणामों पर इस लहर का स्पष्ट प्रभाव देखा गया है, जिससे स्थापित सरकारों को सत्ता त्यागनी पड़ी है। यह लोकतंत्र की एक जीवंत प्रक्रिया है जहाँ मतदाता प्रदर्शन के आधार पर अपने प्रतिनिधियों को परिवर्तित करने की शक्ति का प्रयोग करते हैं।

164. (B) मध्य भारत में प्रशासनिक सीमाओं का एकीकरण और युक्तिकरण।
1956 में मध्य प्रदेश का निर्माण केवल एक नया राज्य निर्मित करना नहीं था, अपितु मध्य भारत के बिखरे हुए क्षेत्रों को एक सुसंगठित प्रशासनिक इकाई में संयोजित करने का एक विशाल प्रयास था। इस प्रक्रिया में कई लघु रियासतों और प्रशासनिक खंडों का विलय किया गया ताकि एक विशाल और आर्थिक रूप से व्यवहार्य राज्य बन सके। सीमाओं के इस युक्तिकरण का उद्देश्य प्रशासनिक व्यय को न्यून करना और भाषाई एकता के माध्यम से शासन को जनता के अधिक समीप लाना था। इस एकीकरण ने राज्य को एक नई भौगोलिक और राजनीतिक पहचान प्रदान की, जिससे विकास कार्यों को दिशा मिली।

165. (A) A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत मध्य प्रदेश की संसदीय शासन प्रणाली का मूल आधार है। इसका अर्थ है कि संपूर्ण मंत्रिपरिषद एक इकाई के रूप में कार्य करती है और अपने समस्त निर्णयों हेतु विधानसभा के प्रति संयुक्त रूप से जवाबदेह होती है। यदि विधानसभा सरकार की किसी नीति या किसी एक मंत्री के विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देती है, तो इसे संपूर्ण सरकार की विफलता माना जाता है और मुख्यमंत्री सहित समस्त मंत्रियों को अनिवार्य रूप से त्यागपत्र देना पड़ता है। यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि सरकार के भीतर आपसी सामंजस्य और सदन के प्रति निरंतर जवाबदेही बनी रहे।

166. (A) अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक के रूप में प्रमाणित होना आवश्यक है।
मध्य प्रदेश विधानसभा में प्रस्तुत किसी भी विधेयक के धन विधेयक होने या न होने पर संदेह की स्थिति में, विधानसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम और सर्वोपरी होता है। अध्यक्ष को यह प्रमाणित करना होता है कि संबंधित विधेयक विशेष रूप से कर अधिरोपण, धन ऋण लेने या राज्य की संचित निधि से व्यय जैसे वित्तीय मामलों से संबद्ध है। अध्यक्ष द्वारा प्रदान किया गया यह प्रमाण-पत्र ही उस विधेयक को धन विधेयक की विशेष विधायी प्रक्रिया में प्रवेश दिलाता है। यह प्रमाणीकरण राज्यपाल या किसी न्यायालय की जांच के दायरे से बाहर होता है, जो सदन की वित्तीय स्वायत्तता को सुरक्षित रखता है।

167. (B) संघ और राज्य के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी।
मध्य प्रदेश के राज्यपाल की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण और दोहरी है; वे न केवल राज्य के संवैधानिक प्रमुख हैं, अपितु केंद्र और राज्य सरकार के मध्य एक आवश्यक सेतु के रूप में भी कार्य करते हैं। वे राष्ट्रपति को नियमित रूप से राज्य की स्थिति और शासन की सूचना प्रेषित करते हैं, जिससे केंद्र सरकार राज्य की गतिविधियों से अवगत रहती है। यह भूमिका संघीय ढांचे की सुदृढ़ता और केंद्र-राज्य संबंधों में समन्वय बनाए रखने हेतु अनिवार्य है। राज्यपाल का पद यह सुनिश्चित करता है कि राज्य का प्रशासन राष्ट्रीय एकता और संवैधानिक मर्यादाओं के भीतर सुचारू रूप से संचालित हो।

168. (A) छह महीने के भीतर विधानसभा के लिए निर्वाचित होना होगा।
यदि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री नियुक्त होते समय राज्य विधानसभा का सदस्य नहीं है, तो संविधान उन्हें पद ग्रहण करने की अनुमति प्रदान करता है, किंतु एक अनिवार्य समय सीमा के साथ। उन्हें अपनी नियुक्ति की तिथि से निरंतर छह माह की अवधि के भीतर किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होना होगा। यदि वे इस निर्धारित समय के भीतर सदन की सदस्यता प्राप्त करने में विफल रहते हैं, तो उन्हें मुख्यमंत्री के पद से अनिवार्य रूप से त्यागपत्र देना पड़ता है।

Click Here to Buy book on Amazon

यह प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि राज्य का कार्यकारी प्रमुख अनिवार्य रूप से जनता का निर्वाचित प्रतिनिधि हो।

169. (C) राज्यपाल
मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र कब प्रारंभ होगा, इसकी औपचारिक घोषणा करने की संवैधानिक शक्ति राज्य के राज्यपाल के पास है। राज्यपाल समय-समय पर विधानसभा को ऐसे समय और स्थान पर बैठने हेतु आहूत करते हैं जैसा वे उचित समझें। यद्यपि राज्यपाल यह निर्णय मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद के परामर्श पर ही लेते हैं, किंतु सत्र बुलाने का आधिकारिक आदेश उन्हीं के नाम से जारी किया जाता है। संविधान के अनुसार, दो सत्रों के मध्य छह माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए, जिसे सुनिश्चित करना राज्यपाल का दायित्व है।

170. (B) सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति करना।
मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्षी दल का मुख्य कार्य सरकार की नीतियों की रचनात्मक आलोचना करना, बजट का गहन अन्वेषण करना और चर्चाओं के माध्यम से जनहित के मुद्दे उठाना है। विपक्ष शासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु एक प्रहरी के रूप में कार्य करता है। यद्यपि, सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति करना पूर्णतः कार्यपालिका अर्थात सरकार का प्रशासनिक कार्य है, जिसमें विपक्ष की कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं होती। नियुक्तियों की प्रक्रिया लोक सेवा आयोग और सरकारी नियमों के अंतर्गत सरकार द्वारा संचालित की जाती है। विपक्ष केवल इन नियुक्तियों में त्रुटियों पर प्रश्न उठा सकता है।

171. (B) भारत का संविधान
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना, उसका अधिकार क्षेत्र, शक्तियां और कार्यप्रणाली मुख्य रूप से भारत के संविधान द्वारा निर्धारित और परिभाषित हैं। संविधान का अध्याय 5 (अनुच्छेद 214 से 231) विशेष रूप से राज्यों के उच्च न्यायालयों से संबंधित है। इसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति, उनके कार्यकाल, स्थानांतरण और रिट जारी करने की शक्तियों का विस्तृत विवरण है। कोई भी राज्य सरकार या विधायिका उच्च न्यायालय की इन संवैधानिक शक्तियों को न्यून नहीं कर सकती है। संविधान ही न्यायपालिका को एक स्वतंत्र और निष्पक्ष संस्था के रूप में कार्य करने का विधिक आधार और संरक्षण प्रदान करता है।

172. (A) द्विध्रुवीय
मध्य प्रदेश की दलीय व्यवस्था को इसके द्विध्रुवीय स्वरूप के कारण जाना जाता है, जहाँ सत्ता के मुख्य केंद्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी हैं। दशकों से राज्य की राजनीति इन दो प्रमुख राष्ट्रीय दलों के चारों ओर ही केंद्रित रही है। मतदाता सामान्यतः इन दो दलों की विचारधाराओं और नेतृत्व के मध्य ही चयन करते हैं, जिससे किसी तृतीय पक्ष या क्षेत्रीय दल हेतु विशाल चुनावी सफलता प्राप्त करना कठिन हो जाता है। यह द्विध्रुवीय प्रतिस्पर्धा राज्य में राजनीतिक स्थिरता को प्रोत्साहित करती है और अक्सर स्पष्ट बहुमत वाली सरकारों के गठन का मार्ग प्रशस्त करती है।

173. (B) फजल अली
भारत में राज्यों के पुनर्गठन की प्रक्रिया को दिशा प्रदान करने हेतु 1953 में 'राज्य पुनर्गठन आयोग' का गठन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति फजल अली ने की थी। इस आयोग में एच. एन. कुंजरु और के. एम. पणिक्कर सदस्य के रूप में सम्मिलित थे। आयोग ने भाषाई और प्रशासनिक आधार पर राज्यों की सीमाओं को पुनः निर्धारित करने की महत्वपूर्ण अनुशंसाएं प्रदान कीं। इन्हीं अनुशंसाओं के आधार पर 1956 में आधुनिक मध्य प्रदेश सहित देश के कई अन्य राज्यों का निर्माण हुआ। फजल अली की अध्यक्षता में निर्मित इस रिपोर्ट ने स्वतंत्र भारत के राजनीतिक एकीकरण में ऐतिहासिक भूमिका निर्वहन की।

174. (A) छत्तीसगढ़ को अपने खनिज समृद्ध क्षेत्रों का हस्तांतरण।
वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश के विभाजन के पश्चात, राज्य के आर्थिक और भौगोलिक परिदृश्य में एक विशाल परिवर्तन आया। अविभाजित राज्य का खनिज और वन संपदा से परिपूर्ण एक बहुत बड़ा भाग नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य में चला गया। इस हस्तांतरण के कारण मध्य प्रदेश को अपने राजस्व और औद्योगिक विकास की रणनीतियों को पुनः परिभाषित करना पड़ा। यद्यपि राज्य ने पश्चात में कृषि और सेवा क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की, किंतु खनिजों की प्रचुरता वाली वह पूर्व स्थिति अब छत्तीसगढ़ के पास है। यह परिवर्तन विभाजन के पश्चात मध्य प्रदेश के आर्थिक विकास का प्रमुख निर्धारक बना।

175. (A) 1, 2, 3, 4
भारत के संविधान में राज्यों के शासन ढांचे से संबंधित प्रावधान एक तार्किक और व्यवस्थित क्रम में प्रदान किए गए हैं। संविधान के भाग 6 में सर्वप्रथम राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में 'राज्यपाल' (अनुच्छेद 153) का उल्लेख है। इसके पश्चात वास्तविक कार्यपालिका के रूप में 'मंत्रिपरिषद' (अनुच्छेद 163) के विषय में बताया गया है। फिर विधायी व्यवस्था हेतु 'राज्य विधायिका' (अनुच्छेद 168) के प्रावधान आते हैं। अंत में, राज्य की न्यायिक व्यवस्था को संचालित करने हेतु 'राज्यों के उच्च न्यायालयों' (अनुच्छेद 214) का विवरण दिया गया है। यह क्रम राज्य शासन की संरचना को स्पष्ट करता है।

176. (A) राज्य विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा हो।
संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत, मध्य प्रदेश के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की विशेष विधायी शक्ति प्राप्त है। इस शक्ति का प्रयोग वे केवल तभी कर सकते हैं जब राज्य विधानसभा का सत्र क्रियाशील न हो और ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएं जिनमें तत्काल विधिक कार्रवाई आवश्यक हो। राज्यपाल द्वारा जारी यह अध्यादेश राज्य विधायिका द्वारा पारित कानून के समान ही प्रभावी होता है। यद्यपि, विधानसभा का सत्र प्रारंभ होने के छह सप्ताह के भीतर इसे सदन द्वारा अनुमोदित किया जाना अनिवार्य है, अन्यथा यह निष्प्रभावी हो जाता है। यह एक असाधारण विधायी उपाय है।

177. (A) कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री।
मध्य प्रदेश की मंत्रिपरिषद एक संगठित त्रि-स्तरीय संरचना है जिसे प्रशासनिक कार्यकुशलता हेतु निर्मित किया गया है।

NODIA

इसमें शीर्ष पर कैबिनेट मंत्री होते हैं जो गृह, वित्त और कृषि जैसे महत्वपूर्ण विभागों के प्रभारी होते हैं और नीति-निर्माण में मुख्य भूमिका निर्वहन करते हैं। द्वितीय स्तर पर राज्य मंत्री होते हैं, जिन्हें कभी-कभी विशिष्ट विभागों का स्वतंत्र प्रभार प्रदान किया जाता है या वे कैबिनेट मंत्रियों की सहायता करते हैं। तृतीय स्तर पर उप मंत्री होते हैं जो प्रशासनिक कार्यों में सहयोग करते हैं। यह संपूर्ण टीम मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एकजुट होकर राज्य के शासन का संचालन करती है।

178. (C) विधायी और वित्तीय शक्तियाँ हैं
मध्य प्रदेश विधानसभा की सर्वोच्चता उसके द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली विधायी और वित्तीय शक्तियों में निहित है। विधानसभा का मुख्य कार्य राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून निर्मित करना है जो राज्य के विकास और प्रशासन को निर्देशित करते हैं। इसके साथ ही, राज्य के वित्त पर विधानसभा का पूर्ण नियंत्रण होता है। वार्षिक बजट और समस्त वित्तीय व्यय हेतु विधानसभा की स्वीकृति अनिवार्य है। बिना विधायी अनुमति के सरकार न तो कर अधिरोपित कर सकती है और न ही धन व्यय कर सकती है। ये शक्तियां कार्यपालिका पर जनता के प्रतिनिधियों का प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करती हैं।

179. (B) रिक्त हो
मध्य प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष की भूमिका तब अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है जब अध्यक्ष का पद किसी कारणवश रिक्त हो जाता है। संविधान के अनुसार, अध्यक्ष की अनुपस्थिति, त्यागपत्र, निधन या पद से विमुक्ति की स्थिति में उपाध्यक्ष ही अध्यक्ष के समस्त कर्तव्यों और शक्तियों का निर्वहन करते हैं। वे सदन की कार्यवाही का संचालन करते हैं, मर्यादा बनाए रखते हैं और विधायी प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित करते हैं। उपाध्यक्ष को वही शक्तियां और विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं जो उस समय अध्यक्ष के पास होते। यह व्यवस्था सदन की निरंतरता और विधायी कामकाज में किसी भी अवरोध को रोकने हेतु की गई है।

180. (A) P-4, Q-1, R-3, S-2
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की शक्तियों का वर्गीकरण उसके विभिन्न क्षेत्राधिकारों के माध्यम से होता है। मूल क्षेत्राधिकार का अर्थ है उन प्रकरणों को सीधे सुनना जिन्हें प्रथम बार न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। अपीलीय क्षेत्राधिकार के तहत उच्च न्यायालय निचली अदालतों के निर्णयों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करता है। पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार उसे अधीनस्थ न्यायालयों की कार्यप्रणाली पर नियंत्रण और अधीक्षण की शक्ति प्रदान करता है। रिट क्षेत्राधिकार के माध्यम से न्यायालय मौलिक अधिकारों के संरक्षण हेतु महत्वपूर्ण निर्देश और आदेश जारी करता है। ये समस्त शक्तियाँ मिलकर राज्य में निष्पक्ष न्याय प्रणाली सुनिश्चित करती हैं।

181. (A) राज्य के चुनावों का राष्ट्रीयकरण।
जब राज्य विधानसभा निर्वाचनों में मतदाता स्थानीय मुद्दों या क्षेत्रीय नेतृत्व के स्थान पर राष्ट्रीय स्तर के किसी विशाल नेता के व्यक्तित्व, आकर्षण या राष्ट्रीय मुद्दों से प्रभावित होकर मतदान करते हैं, तो इस घटना को 'राज्य के चुनावों का राष्ट्रीयकरण' कहा जाता है। मध्य प्रदेश में भी अक्सर यह देखा गया है कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार या किसी राष्ट्रीय नेता की लोकप्रियता का प्रभाव राज्य की विधानसभा सीटों के परिणामों पर पड़ता है। यह दर्शाता है कि मतदाता अब राज्य की राजनीति को देश की व्यापक राजनीतिक दिशा से जोड़कर देखने लगे हैं, जिससे राष्ट्रीय लहर क्षेत्रीय समीकरणों को प्रभावित कर सकती है।

182. (A) मध्य प्रांत एवं बरार
1956 में आधुनिक मध्य प्रदेश के गठन हेतु भाषाई एकरूपता को मुख्य आधार बनाया गया था। इस प्रक्रिया में पूर्ववर्ती मध्य प्रांत एवं बरार के हिंदी भाषी जिलों को सम्मिलित किया गया, जबकि इसी प्रांत के मराठी भाषी जिलों को बॉम्बे राज्य में स्थानांतरित कर दिया गया। इसके साथ ही मध्य भारत की रियासतें, विंध्य प्रदेश और भोपाल राज्य को संयोजित कर एक विशाल भौगोलिक इकाई निर्मित की गई। इस एकीकरण ने विभिन्न लघु प्रशासनिक इकाइयों को समाप्त कर एक एकीकृत हिंदी भाषी राज्य को जन्म दिया। यह भाषाई पुनर्गठन स्वतंत्र भारत के राजनीतिक मानचित्र को व्यवस्थित करने का निर्णायक कदम था।

183. (C) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की नियुक्ति औपचारिक रूप से राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 164 में प्रावधान है। यद्यपि, राज्यपाल की यह शक्ति पूर्णतः स्वैच्छिक या मनमानी नहीं है। वे सुस्थापित लोकतांत्रिक परंपराओं और नियमों से आबद्ध होते हैं। सामान्यतः राज्यपाल विधानसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त करने वाले दल या गठबंधन के नेता को ही मुख्यमंत्री नियुक्त करने हेतु बाध्य हैं। केवल त्रिशंकु विधानसभा जैसी असाधारण परिस्थितियों में ही वे अपनी विवेकाधीन शक्ति का सीमित प्रयोग कर सकते हैं। अतः मुख्यमंत्री की नियुक्ति व्यक्तिगत पसंद के स्थान पर चुनावी जनादेश पर आधारित होती है।

184. (A) की किसी भी न्यायालय द्वारा जांच नहीं की जा सकती।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार, राज्यपाल को उनके कार्यों के संचालन हेतु मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदत्त परामर्श की गोपनीयता और स्वायत्तता को सुरक्षित रखा गया है। इसका अर्थ यह है कि राज्यपाल और मंत्रियों के मध्य होने वाले संवाद या प्रदत्त विशेष परामर्श की किसी भी न्यायालय में जांच नहीं की जा सकती। यह प्रावधान इसलिए किया गया है ताकि कार्यपालिका बिना किसी न्यायिक हस्तक्षेप के भय के स्वतंत्र रूप से चर्चा कर सके और निर्णय ले सके। यद्यपि, मंत्रिपरिषद के निर्णयों के आधार पर किए गए कार्यों की न्यायिक समीक्षा कुछ विशेष परिस्थितियों में संभव है, किंतु वास्तविक 'परामर्श' विधिक जांच के परे है।

185. (A) केवल 1 और 2
मध्य प्रदेश की विधायिका का ढांचा एकसदनीय है, जहाँ विधानसभा राज्य विधायिका का एकमात्र और निचला सदन है। विधानसभा के सुचारु संचालन हेतु अध्यक्ष मुख्य पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं और सदन की गरिमा बनाए

Downloaded from www.pdf.tube

मंत्रिपरिषद में ही निहित होती हैं। मुख्यमंत्री शासन का वास्तविक मुखिया होता है जो राज्य की नीतियों और निर्णयों को निर्देशित करता है। मंत्रिपरिषद ही सामूहिक रूप से प्रशासन के संचालन और कानून क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी होती है। राज्यपाल प्रायः मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार ही अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि शासन की बागडोर जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास ही रहे।

119. (B) बजट पारित करने के माध्यम से सभी खर्चों को अधिकृत करना।
मध्य प्रदेश विधानसभा का राज्य के वित्त पर सर्वोच्च नियंत्रण होता है, जो "प्रतिनिधित्व के बिना कोई कर नहीं" के लोकतांत्रिक सिद्धांत पर आधारित है। सरकार बिना विधानसभा की स्वीकृति के न तो कोई कर अधिरोपित कर सकती है और न ही संचित निधि से धन व्यय कर सकती है। प्रत्येक वर्ष बजट के माध्यम से सरकार को अपने आगामी व्यय का विवरण सदन के समक्ष प्रस्तुत करना होता है, जिसे विधानसभा विस्तार से चर्चा के पश्चात पारित करती है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि सार्वजनिक धन का उपयोग केवल उन्हीं कार्यों हेतु हो जिन्हें जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों ने अनुमति प्रदान की है।

120. (A) A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष की भूमिका केवल आलोचना तक सीमित नहीं है, अपितु यह लोकतांत्रिक संतुलन बनाए रखने का एक अनिवार्य भाग है। संसदीय लोकतंत्र में सरकार को अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने से रोकने हेतु एक सतर्क और रचनात्मक विपक्ष की आवश्यकता होती है। विपक्ष बहसों, प्रश्नों और प्रस्तावों के माध्यम से सरकार को अपनी नीतियों को स्पष्ट करने और त्रुटियों को सुधारने हेतु बाध्य करता है। इस प्रक्रिया से यह सुनिश्चित होता है कि कार्यपालिका अपने उत्तरदायित्व को गंभीरता से ले और शासन में पारदर्शिता तथा जनता के प्रति जवाबदेही बनी रहे।

121. (B) भारत के राष्ट्रपति।
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया अत्यंत औपचारिक और उच्च स्तरीय है। यद्यपि वे राज्य के उच्च न्यायालय में कार्यरत होते हैं, किंतु उनकी नियुक्ति का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास सुरक्षित है। राष्ट्रपति यह निर्णय भारत के मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य के राज्यपाल और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ परामर्श करने के पश्चात लेते हैं। यह व्यवस्था न्यायपालिका की स्वतंत्रता और अखिल भारतीय स्वरूप को बनाए रखने हेतु की गई है। न्यायाधीशों की नियुक्ति में राज्य के मुख्यमंत्री या विधायिका की कोई प्रत्यक्ष कार्यकारी भूमिका नहीं होती है।

122. (A) विभाजित मत (स्प्लिट-टिकट वोटिंग)
मध्य प्रदेश में अक्सर यह देखा गया है कि मतदाता विधानसभा निर्वाचन और लोकसभा निर्वाचन में भिन्न-भिन्न राजनीतिक दलों को प्राथमिकता देते हैं। इस व्यवहार को 'विभाजित मत' कहा जाता है। इसका अर्थ है कि मतदाता राज्य की स्थानीय समस्याओं और नेतृत्व हेतु एक दल को चुनते हैं, जबकि राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति जैसे केंद्रीय मुद्दों हेतु दूसरे दल को। यह प्रवृत्ति प्रदर्शित करती है कि राज्य का मतदाता पर्याप्त जागरूक है और वह मुद्दों की गंभीरता और स्तर के आधार पर अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग अत्यंत विवेकपूर्ण ढंग से करता है।

123. (B) हैदराबाद के निजाम का क्षेत्र।
1956 में मध्य प्रदेश का गठन विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों और रियासतों को एकत्रित कर किया गया था, जिनमें मध्य प्रांत एवं बरार, मध्य भारत की रियासतें और विंध्य प्रदेश सम्मिलित थे। हैदराबाद के निजाम का क्षेत्र मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों के मध्य विभाजित हुआ था और वह मध्य प्रदेश के गठन का भाग नहीं बना। मध्य प्रदेश के निर्माण का मुख्य उद्देश्य हिंदी भाषी क्षेत्रों का एकीकरण करना था। इस प्रक्रिया में केवल उन्हीं क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया था जहाँ हिंदी मुख्य भाषा थी और जिनका भौगोलिक संबंध इस मध्य भाग से था।

124. (D) अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन
यदि मध्य प्रदेश में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए जहाँ राज्य का प्रशासन भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुसार संचालित करना असंभव हो, तो राज्यपाल अपना विवरण राष्ट्रपति को प्रेषित कर सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत इस विवरण के आधार पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में, मंत्रिपरिषद भंग कर दी जाती है और राज्य की कार्यकारी शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास चली जाती हैं, जिनका प्रयोग वे राज्यपाल के माध्यम से करते हैं। यह एक असाधारण संवैधानिक उपाय है जिसका उद्देश्य राज्य में संवैधानिक व्यवस्था को पुनः स्थापित करना है।

125. (A) राज्यपाल
मध्य प्रदेश में मंत्रिपरिषद के सदस्य संवैधानिक रूप से राज्य के राज्यपाल के प्रसादपर्यंत अपना पद धारण करते हैं। इसका अर्थ है कि मंत्रियों की नियुक्ति और पदमुक्ति औपचारिक रूप से राज्यपाल द्वारा ही की जाती है। यद्यपि, व्यावहारिक रूप से राज्यपाल यह शक्ति मुख्यमंत्री के परामर्श पर ही प्रयोग करते हैं। यदि मुख्यमंत्री किसी मंत्री से त्यागपत्र की अपेक्षा करते हैं या उन्हें हटाने की अनुशंसा करते हैं, तो राज्यपाल उन्हें पदमुक्त कर देते हैं। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री का नेतृत्व प्रभावी बना रहे और पूरी सरकार एक ही नीतिगत दिशा में एकजुट होकर कार्य कर सके।

126. (A) P-3, Q-2, R-1, S-4
विधायी शब्दावली में प्रत्येक शब्द का एक विशिष्ट और महत्वपूर्ण अर्थ होता है। सत्रावसान का अर्थ है विधानसभा के पूर्ण सत्र की समाप्ति करना, जो राज्यपाल द्वारा किया जाता है। स्थगन का तात्पर्य सदन की केवल एक बैठक की समाप्ति से है, जो अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। विघटन वर्तमान विधानसभा के कार्यकाल को ही पूर्णतः समाप्त कर देता है, जिससे नए निर्वाचन अनिवार्य हो जाते हैं। गणपूर्ति वह न्यूनतम सदस्य संख्या है जो सदन की कार्यवाही को विधिक बनाने हेतु उपस्थित होनी

NODIA

लोकसभा अध्यक्ष केंद्र में सदन की मर्यादा, सदस्यों के विशेषाधिकारों और विधायी प्रक्रिया का संचालन करते हैं, वही उत्तरदायित्व राज्य स्तर पर विधानसभा अध्यक्ष का होता है। दोनों ही अपने-अपने सदन के मुख्य पीठासीन अधिकारी होते हैं और सदन के भीतर उनके निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होते हैं। वे निष्पक्षता के प्रतीक होते हैं और सदन की स्वायत्तता की रक्षा करते हैं। यह समानता भारतीय विधायी प्रणाली की एकरूपता को प्रदर्शित करती है।

194. (B) राज्यपाल को सलाह देने का क्षेत्राधिकार
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पास व्यापक न्यायिक शक्तियां हैं, जिनमें मूल क्षेत्राधिकार (सीधे प्रकरणों की सुनवाई), अपीलीय क्षेत्राधिकार (निचली अदालतों के निर्णयों के विरुद्ध अपील) और पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार (अधीनस्थ न्यायालयों की निगरानी) सम्मिलित हैं। यद्यपि, राज्यपाल को विधिक मामलों पर परामर्श देने का अधिकार उच्च न्यायालय के पास नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को परामर्श देने का कार्य केवल भारत के उच्चतम न्यायालय का है। राज्यपाल अपने विधिक परामर्श हेतु सामान्यतः राज्य के महाधिवक्ता पर निर्भर करते हैं। अतः सलाहकार भूमिका उच्च न्यायालय के संवैधानिक अधिकार क्षेत्र का भाग नहीं है।

195. (A) भारत निर्वाचन आयोग
मध्य प्रदेश में विधानसभा और लोकसभा निर्वाचनों का निष्पक्ष और स्वतंत्र संचालन भारत निर्वाचन आयोग का उत्तरदायित्व है। यह एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है जो निर्वाचन तिथियों की घोषणा, मतदाता सूचियों की तैयारी, आदर्श चुनाव आचार संहिता क्रियान्वित करने और परिणामों की घोषणा तक की संपूर्ण प्रक्रिया की निगरानी करता है। यद्यपि स्थानीय निकायों (पंचायत और नगरपालिका) के निर्वाचन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा कराए जाते हैं, किंतु विधायी और राष्ट्रीय निर्वाचनों पर नियंत्रण पूर्णतः भारत निर्वाचन आयोग के पास होता है। यह व्यवस्था राज्य की चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता और लोकतांत्रिक शुचिता को बनाए रखने हेतु अनिवार्य है।

196. (A) अनुच्छेद 3
वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश का विभाजन और छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों के माध्यम से संपन्न हुआ था। यह अनुच्छेद संसद को किसी राज्य में से उसका राज्यक्षेत्र पृथक करके नया राज्य निर्मित करने, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने या उनके नाम परिवर्तित करने का अनन्य अधिकार प्रदान करता है। इसी संवैधानिक प्रावधान का प्रयोग करते हुए 'मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000' पारित किया गया। इस प्रक्रिया हेतु राष्ट्रपति की अनुशंसा और संबंधित राज्य विधानसभा के विचारों को जानना आवश्यक होता है, किंतु अंतिम निर्णय लेने की शक्ति पूर्णतः देश की संसद के पास ही सुरक्षित है।

197. (D) उच्च न्यायालय के न्यायाधीश
मध्य प्रदेश के राज्यपाल के पास राज्य प्रशासन से संलग्न कई महत्वपूर्ण नियुक्तियों की शक्ति है, जिनमें मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद के सदस्य, महाधिवक्ता और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सम्मिलित हैं। यद्यपि, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है। संविधान के अनुसार, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल की भूमिका इस प्रक्रिया में केवल एक परामर्शदाता की होती है, जहाँ राष्ट्रपति नियुक्ति से पूर्व संबंधित राज्य के राज्यपाल से विचार विमर्श करते हैं। यह न्यायिक स्वतंत्रता और उच्च न्यायालय के संघीय स्वरूप को बनाए रखने हेतु आवश्यक है।

198. (A) अनावश्यक रूप से बड़े मंत्रिमंडल और राजनीतिक अनैतिक दलबदल।
संविधान के 91वें संशोधन के माध्यम से मध्य प्रदेश सहित समस्त राज्यों में मंत्रिपरिषद के आकार को विधानसभा सीटों के 15 प्रतिशत तक सीमित कर दिया गया है। इस संवैधानिक प्रावधान का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक भ्रष्टाचार और अनैतिक दलबदल पर अंकुश लगाना है, जहाँ अक्सर विधायकों को मंत्री पद का प्रलोभन देकर दल परिवर्तित करने हेतु प्रेरित किया जाता था। इसके अतिरिक्त, यह अनावश्यक रूप से विशाल मंत्रिमंडल के गठन को रोककर सरकारी कोष पर पड़ने वाले वित्तीय भार को भी न्यून करता है। यह सीमा प्रशासन को अधिक कार्यकुशल बनाती है और सत्ता के दुरुपयोग की संभावना को काफी सीमा तक नियंत्रित करती है।

199. (A) लोक लेखा समिति के माध्यम से
मध्य प्रदेश विधानसभा कार्यपालिका की वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु 'लोक लेखा समिति' जैसे सशक्त विधायी उपकरणों का प्रयोग करती है। यह समिति नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्टों की सूक्ष्म जांच करती है ताकि यह देखा जा सके कि सरकार ने जनता के धन को उसी उद्देश्य हेतु व्यय किया है जिसके लिए उसे अधिकृत किया गया था। समिति यह सुनिश्चित करती है कि सरकारी व्यय में कोई वित्तीय अनियमितता, अपव्यय या भ्रष्टाचार न हो। यह विधायी निगरानी राज्य के संसाधनों के पारदर्शी और उत्तरदायी प्रबंधन हेतु एक अत्यंत प्रभावी और अनिवार्य तंत्र के रूप में कार्य करती है।

200. (A) विपक्ष के सबसे बड़े दल को औपचारिक दर्जा और भूमिका प्रदान करने के लिए।
मध्य प्रदेश विधानसभा में "विपक्ष के नेता" के पद को आधिकारिक मान्यता प्रदान करना लोकतांत्रिक व्यवस्था की परिपक्वता का प्रतीक है। इसका मुख्य उद्देश्य विपक्ष के विशालतम दल को एक संवैधानिक और विधायी दर्जा प्रदान करना है, जिससे वह सरकार की नीतियों की व्यवस्थित आलोचना कर सके। यह पद न केवल विपक्ष को एक चेहरा और स्वर प्रदान करता है, अपितु यह भी सुनिश्चित करता है कि महत्वपूर्ण नियुक्तियों और निर्णयों में विपक्षी दल का दृष्टिकोण भी सम्मिलित हो। विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री के समान दर्जा और सुविधाएं देना उनके पद की गरिमा और लोकतांत्रिक शासन में उनकी अपरिहार्य भूमिका को रेखांकित करता है।

Click Here to Buy book on Amazon

औपचारिक नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, किंतु वे इस कार्य में पूर्णतः मुख्यमंत्री के परामर्श से आबद्ध होते हैं। मुख्यमंत्री ही यह निश्चित करते हैं कि उनके दल या गठबंधन के किन सदस्यों को मंत्री बनाया जाना चाहिए और उन्हें कौन से विभाग आवंटित किए जाने चाहिए। राज्यपाल अपनी इच्छा से किसी को मंत्री नियुक्त नहीं कर सकते। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक एकजुट और कार्यात्मक टीम के रूप में कार्य करे, जिसे विधानसभा का समर्थन प्राप्त हो।

249. (A) 25 वर्ष
मध्य प्रदेश विधानसभा का सदस्य बनने हेतु भारत के संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। कोई भी भारतीय नागरिक जो इस आयु सीमा को पार कर चुका है और मतदाता सूची में पंजीकृत है, विधानसभा निर्वाचन लड़ने हेतु पात्र है। यह आयु सीमा इसलिए निर्धारित की गई है ताकि विधायी कार्यों हेतु परिपक्वता और अनुभव का एक प्रारंभिक स्तर सुनिश्चित हो सके। इसके अतिरिक्त, उम्मीदवार को किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए और उसे मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। यह पात्रता मापदंड राज्य के युवाओं को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने और नेतृत्व करने का अवसर प्रदान करता है।

250. (A) P-3, Q-1, R-4, S-2
मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था में प्रत्येक संवैधानिक इकाई की एक विशिष्ट और महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्यपाल राज्य के नाममात्र के कार्यकारी प्रमुख होते हैं, जो संविधान की गरिमा का प्रतिनिधित्व करते हैं। मुख्यमंत्री वास्तविक कार्यकारी अधिकारी होते हैं जो शासन का संचालन करते हैं। विधानसभा अध्यक्ष सदन के संरक्षक होते हैं जो विधायकों की शक्तियों और विशेषाधिकारों की रक्षा करते हैं। उच्च न्यायालय संविधान और नागरिकों के मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में कार्य करता है। ये समस्त अंग मिलकर राज्य के लोकतांत्रिक ढांचे को सुदृढ़, पारदर्शी और उत्तरदायी बनाते हैं, जिससे शक्तियों का संतुलन और कानून का शासन सुनिश्चित होता है।

251. (A) जनता को नीतियों का एक वैकल्पिक समूह प्रदान करना।
विधानसभा में विपक्ष की भूमिका केवल सरकार की त्रुटियों को उजागर करने तक सीमित नहीं है, अपितु वह लोकतंत्र में एक 'वैकल्पिक सरकार' की भांति कार्य करती है। विपक्ष का एक महत्वपूर्ण कार्य जनता के समक्ष शासन हेतु एक भिन्न और श्रेष्ठ नीतियों का विकल्प प्रस्तुत करना है। जब सरकार किसी विषय पर विफल होती है, तो विपक्ष अपनी प्रस्तावित योजनाओं के माध्यम से यह प्रदर्शित करता है कि वही कार्य अधिक कुशलता से कैसे किया जा सकता था। यह प्रतिस्पर्धा मतदाताओं को अगले निर्वाचन में एक सूचित निर्णय लेने में सहायता प्रदान करती है और सत्तारूढ़ दल को अपनी नीतियों में सुधार हेतु निरंतर प्रेरित करती रहती है।

252. (A) किसी व्यक्ति की हिरासत की वैधता पर प्रश्न उठाना।
'बंदी प्रत्यक्षीकरण' रिट मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा जारी की जाने वाली व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सर्वाधिक महत्वपूर्ण रक्षक है। यह रिट तब जारी की जाती है जब किसी व्यक्ति को पुलिस या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा अवैध रूप से या बिना किसी विधिक आधार के हिरासत में लिया गया हो। इस आदेश के माध्यम से न्यायालय हिरासत में लेने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह उस व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष शारीरिक रूप से प्रस्तुत करे और उसकी हिरासत का विधिक कारण स्पष्ट करे। यदि न्यायालय हिरासत को अवैध पाता है, तो वह उस व्यक्ति को तत्काल विमुक्त करने का आदेश प्रदान करता है।

253. (A) राजनीतिक व्यवस्था के प्रति इसके नागरिकों के प्रचलित दृष्टिकोण, विश्वास और मूल्य।
मध्य प्रदेश की 'राजनीतिक संस्कृति' उन सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारकों का समूह है जो यहाँ के निवासियों के राजनीतिक आचरण को निर्देशित करते हैं। इसमें राज्य के लोगों का लोकतंत्र के प्रति विश्वास, मतदान की उनकी आदतें, सामाजिक न्याय और विकास के प्रति उनके विचार और राजनीतिक नेतृत्व के प्रति उनकी अपेक्षाएं सम्मिलित हैं। यह संस्कृति राज्य की ऐतिहासिक विरासत, भाषाई पहचान और ग्रामीण-शहरी समाज के मूल्यों से निर्मित होती है। यह राजनीतिक व्यवस्था को स्थिरता प्रदान करती है और यह निर्धारित करती है कि शासन और सत्ता के प्रति आम जनता का क्या दृष्टिकोण है, जो अंततः राज्य के लोकतांत्रिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है।

254. (A) भाषा
1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम का मुख्य प्रेरणा स्रोत देश भर में भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण की प्रबल जन-मांग थी। स्वतंत्र भारत में यह माना गया कि यदि प्रशासनिक सीमाएँ प्रमुख भाषाओं के क्षेत्रों के अनुरूप होंगी, तो शासन अधिक प्रभावी होगा और जनता की अपनी संस्कृति से जुड़ाव बना रहेगा। मध्य प्रदेश का गठन भी इसी भाषाई आधार पर हिंदी भाषी क्षेत्रों को एकीकृत करने के उद्देश्य से किया गया था। इस प्रक्रिया ने विभिन्न रियासतों को एक भाषाई सूत्र में संयोजित कर एक विशाल राज्य को जन्म दिया। यह पुनर्गठन भारतीय लोकतंत्र में सांस्कृतिक और भाषाई विविधता के सम्मान का एक महत्वपूर्ण प्रमाण है।

255. (A) कुछ स्थितियों में विवेकाधीन शक्तियां हैं।
मध्य प्रदेश के राज्यपाल प्रायः मंत्रिपरिषद के परामर्श पर कार्य करते हैं, किंतु उनकी सर्वाधिक विशिष्ट शक्ति उनकी विवेकाधीन शक्तियाँ हैं, जहाँ वे स्वतंत्र निर्णय ले सकते हैं। इनमें त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में मुख्यमंत्री की नियुक्ति, सरकार को बहुमत सिद्ध करने हेतु कहना, या किसी विवादास्पद विधेयक को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित करना सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त, अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुशंसा करना भी उनके विवेक पर निर्भर करता है। ये शक्तियां उन्हें केवल एक औपचारिक प्रमुख से ऊपर उठाकर राज्य की संवैधानिक स्थिरता के रक्षक और केंद्र-राज्य समन्वय की कड़ी के रूप में स्थापित करती हैं।

NODIA

परामर्श के स्वतंत्र निर्णय ले सकते हैं। ये समस्त तत्व मिलकर राज्य की प्रशासनिक संरचना को व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करते हैं।

209. (A) किसी सार्वजनिक पद पर किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच करने के लिए।
'अधिकार-पृच्छा' रिट मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा जारी की जाने वाली एक विशिष्ट न्यायिक शक्ति है। यह रिट तब जारी की जाती है जब किसी व्यक्ति पर यह संदेह होता है कि उसने किसी सार्वजनिक पद को अवैध रूप से या बिना किसी विधिक अधिकार के धारण कर लिया है। इस रिट के माध्यम से न्यायालय उस व्यक्ति से पूछता है कि "वह किस अधिकार से" उस पद पर आसीन है। यदि न्यायालय संतुष्ट नहीं होता, तो वह उस व्यक्ति को पदमुक्त करने का आदेश प्रदान कर सकता है। यह रिट सार्वजनिक पदों के दुरुपयोग को रोकने और कानून के शासन को बनाए रखने में सहायक होती है।

210. (A) उम्मीदवार का जाति और सामुदायिक संबंध।
ग्रामीण मध्य प्रदेश में चुनावी राजनीति और मतदान व्यवहार सामाजिक संरचनाओं से गहराई से संलग्न है। यहाँ मतदाता अक्सर उम्मीदवार की व्यक्तिगत योग्यता के साथ-साथ उसकी जाति और सामुदायिक पहचान को भी अत्यंत महत्व प्रदान करते हैं। राजनीतिक दल भी उम्मीदवारों का चयन करते समय क्षेत्रीय जातिगत समीकरणों का सूक्ष्म विश्लेषण करते हैं ताकि अधिकतम जनसमर्थन अर्जित किया जा सके। यद्यपि विकास और स्थानीय मुद्दे भी धीरे-धीरे महत्वपूर्ण हो रहे हैं, किंतु जाति और समुदाय आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में मतदाताओं को गोलबंद करने और चुनावी परिणामों को प्रभावित करने वाला एक प्राथमिक और शक्तिशाली कारक बना हुआ है।

211. (C) संसद के एक अधिनियम द्वारा
वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश का विभाजन और छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण भारत की संसद द्वारा पारित 'मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000' के माध्यम से संपन्न हुआ था। भारत के संविधान का अनुच्छेद 3 संसद को यह अनन्य शक्ति प्रदान करता है कि वह कानून निर्मित कर नए राज्यों का गठन कर सके या विद्यमान राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित कर सके। इस प्रक्रिया हेतु राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति और राज्य विधानसभा के विचारों को जानना आवश्यक होता है, किंतु अंतिम विधिक निर्णय संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित अधिनियम ही होता है। यह विभाजन प्रशासनिक सुगमता के उद्देश्य से था।

212. (B) राष्ट्रपति का निर्णय (सहमति देना या रोकना) अंतिम होता है।
जब मध्य प्रदेश के राज्यपाल विधानसभा द्वारा पारित किसी विधेयक को अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित करते हैं, तो उस विधेयक का भविष्य पूर्णतः राष्ट्रपति के निर्णय पर निर्भर हो जाता है। राष्ट्रपति उस विधेयक पर अपनी सहमति प्रदान कर सकते हैं, उसे रोक सकते हैं या विधानसभा को पुनर्विचार हेतु प्रत्यावर्तित कर सकते हैं। यदि राष्ट्रपति अपनी सहमति प्रदान नहीं करते हैं, तो वह विधेयक कानून नहीं बन सकता और राज्यपाल या विधानसभा के पास उसे बलात् लागू करने की कोई शक्ति नहीं होती। इस संदर्भ में राष्ट्रपति का निर्णय सर्वोच्च और अंतिम होता है, जो केंद्र की संघीय निगरानी को प्रदर्शित करता है।

213. (C) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संबंध में संवैधानिक प्रावधान पर्याप्त लचीले हैं। यह अनिवार्य नहीं है कि नियुक्ति के समय व्यक्ति विधानसभा का सदस्य ही हो। संविधान के अनुसार, राज्यपाल किसी भी ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकते हैं, जिसे विधानसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त होने की संभावना हो। यद्यपि, ऐसे व्यक्ति हेतु यह अनिवार्य शर्त है कि वह अपनी नियुक्ति की तिथि से छह माह के भीतर विधानसभा हेतु निर्वाचित हो जाए। यदि वह इस समय सीमा में सदस्यता प्राप्त करने में विफल रहता है, तो उसे अपना पद त्यागना पड़ता है। यह नियम प्रशासनिक निरंतरता और लोकतांत्रिक जवाबदेही के मध्य संतुलन निर्मित करता है।

NODIA

214. (C) स्वयं विधानसभा द्वारा
संविधान के अनुच्छेद 208 के तहत, मध्य प्रदेश विधानसभा को यह स्वायत्त अधिकार प्राप्त है कि वह सदन की कार्यवाही और अपने कार्यों के संचालन हेतु स्वयं नियम निर्मित कर सके। ये नियम विधानसभा की आंतरिक मर्यादा, चर्चाओं के संचालन, मतदान की प्रक्रिया और सदस्यों के आचरण को निर्देशित करते हैं। चूंकि प्रत्येक सदन अपने कार्यों हेतु स्वतंत्र होता है, इसलिए ये नियम राज्यपाल या संसद द्वारा अधिरोपित नहीं किए जा सकते। विधानसभा की यह स्वायत्तता सुनिश्चित करती है कि विधायी कार्य बिना किसी बाह्य हस्तक्षेप के सुचारू रूप से संचालित हों। आवश्यकतानुसार विधानसभा इन नियमों में संशोधन करने का भी अधिकार रखती है।

215. (A) A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष की भूमिका सदन में एक निष्पक्ष निर्णायक और पीठासीन अधिकारी की होती है। विधायी मर्यादा को बनाए रखने हेतु यह आवश्यक है कि वे दलीय राजनीति से ऊपर दृष्टिगोचर हों, इसलिए वे सामान्य परिस्थितियों में किसी विधेयक पर प्रथम दृष्टया मतदान नहीं करते हैं। यद्यपि, यदि किसी विषय पर मतदान के दौरान पक्ष और विपक्ष के मत पूर्णतः समान हो जाते हैं, तो अध्यक्ष अपने 'निर्णायक मत' का प्रयोग करते हैं। उनका यह विशेष मत गतिरोध को समाप्त करने और किसी निश्चित निर्णय तक पहुँचने हेतु संवैधानिक रूप से अनिवार्य है। यह व्यवस्था उनकी तटस्थता को सुरक्षित रखती है।

216. (A) न्यायिक पुनरावलोकन
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की वह सर्वोच्च शक्ति, जिसके अंतर्गत वह राज्य विधायिका द्वारा निर्मित किसी कानून की संवैधानिक वैधता की जांच करता है, न्यायिक पुनरावलोकन कहलाती है। यदि न्यायालय को प्रतीत होता है कि कोई कानून भारत के संविधान के किसी मौलिक सिद्धांत या नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो उसके पास उस कानून को असंवैधानिक घोषित करने का अधिकार है। यह शक्ति सुनिश्चित करती है कि राज्य का कोई भी अंग संविधान की

अनुसार ही कार्य करने हेतु संवैधानिक रूप से आबद्ध हैं। यह मुख्यमंत्री और राज्यपाल के मध्य के प्रशासनिक तालमेल का विधिक आधार है।

264. (A) भारत का संविधान।
मध्य प्रदेश विधानसभा की विधायी शक्तियां व्यापक होने के उपरांत भी सर्वोच्च नहीं हैं; वे पूर्णतः भारत के संविधान की मर्यादाओं और सीमाओं के अधीन हैं। विधानसभा केवल उन्हीं विषयों पर कानून निर्मित कर सकती है जो संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची या समवर्ती सूची में प्रदत्त हैं। इसके अतिरिक्त, विधानसभा द्वारा निर्मित कोई भी कानून नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकता और न ही वह संवैधानिक ढांचे के प्रतिकूल हो सकता है। यदि विधानसभा इन सीमाओं का उल्लंघन करती है, तो उच्च न्यायालय के पास 'न्यायिक पुनरावलोकन' की शक्ति है जिससे वह ऐसे कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। संविधान ही विधायी शक्ति का स्रोत और सीमा है।

265. (A) A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
मध्य प्रदेश की दलीय व्यवस्था को एक उत्कृष्ट द्विध्रुवीय मॉडल के रूप में देखा जाता है, जहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के मध्य सीधा मुकाबला रहता है। ऐतिहासिक रूप से, राज्य के मतदाताओं ने अपना समर्थन मुख्य रूप से इन्हीं दो राष्ट्रीय विचारधाराओं के मध्य विभाजित रखा है। इस चुनावी व्यवहार के कारण, किसी भी तृतीय दल या क्षेत्रीय मोर्चे हेतु राज्य स्तर पर निर्णायक शक्ति बनना अत्यंत कठिन हो गया है। निर्वाचनों में अक्सर स्पष्ट बहुमत प्राप्त होता है, जिससे गठबंधन सरकारों की अनिश्चितता न्यून रहती है। यह द्विध्रुवीयता राज्य की राजनीति को स्थिरता प्रदान करती है और मतदाताओं के पास दो सुस्पष्ट और अनुभवी प्रशासनिक विकल्पों के मध्य चयन की सुविधा रहती है।

266. (A) 62 वर्ष की आयु तक।
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद का कार्यकाल आयु पर आधारित है, न कि किसी राजनीतिक दल या सरकार के कार्यकाल पर। संविधान के अनुसार, एक बार नियुक्त होने के पश्चात, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष की अनिवार्य सेवानिवृत्ति आयु प्राप्त करने तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। उन्हें इस आयु से पूर्व केवल विशेष परिस्थितियों में, जैसे स्वयं का त्यागपत्र या संसद में कठिन प्रक्रिया के माध्यम से ही विमुक्त किया जा सकता है। यह निश्चित कार्यकाल और पद की सुरक्षा न्यायाधीशों को किसी भी कार्यकारी या विधायी दबाव के बिना निष्पक्ष और निर्भीक होकर न्याय प्रदान करने की स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है, जो न्यायिक स्वायत्तता का मूल आधार है।

267. (A) नागरिकों की प्राथमिकताओं को सार्वजनिक नीति में बदला जाता है।
लोकतंत्र में चुनावी राजनीति वह गतिशील माध्यम है जिसके द्वारा जनता की आकांक्षाएं और उनकी प्राथमिकताएं सरकार की आधिकारिक नीतियों का रूप ग्रहण करती हैं। निर्वाचन के दौरान, विभिन्न राजनीतिक दल अपने घोषणापत्रों के माध्यम से विकास, सामाजिक कल्याण और प्रशासन के भिन्न-भिन्न मॉडल जनता के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। जब नागरिक किसी विशेष दल को अपना मत प्रदान करते हैं, तो वे वास्तव में उस दल की नीतियों को अपनी स्वीकृति प्रदान करते हैं। इस प्रकार, निर्वाचित सरकार को प्राप्त जनादेश उसे उन वचनों को कानून और कार्यक्रमों में परिवर्तित करने की शक्ति प्रदान करता है जिन्हें जनता ने प्राथमिकता दी है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि शासन का संचालन सदैव जनता की इच्छा और सहमति से हो।

268. (A) 1 नवंबर, 1956 को
मध्य प्रदेश राज्य का वर्तमान ऐतिहासिक स्वरूप 1 नवंबर, 1956 को अस्तित्व में आया। यह दिन राज्य के इतिहास में सर्वाधिक गौरवशाली माना जाता है क्योंकि इसी दिन भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की प्रक्रिया संपन्न हुई थी। इस प्रक्रिया में मध्य भारत, विंध्य प्रदेश, भोपाल और मध्य प्रांत एवं बरार जैसे विभिन्न हिंदी भाषी क्षेत्रों का एकीकरण करके एक विशाल और एकीकृत मध्य प्रदेश का निर्माण किया गया। 1956 के इस गठन ने राज्य को उसकी भौगोलिक सीमाओं के साथ-साथ एक नई राजनीतिक और प्रशासनिक पहचान भी प्रदान की। तब से, 1 नवंबर को प्रतिवर्ष 'मध्य प्रदेश स्थापना दिवस' के रूप में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है।

269. (A) बेहतर प्रशासनिक दक्षता और केंद्रित क्षेत्रीय विकास।
वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश का विभाजन मुख्य रूप से इस उद्देश्य से किया गया था कि शासन की पहुंच को राज्य के दूरस्थ और पिछड़े क्षेत्रों तक अधिक प्रभावी ढंग से पहुँचाया जा सके। तत्कालीन विशाल मध्य प्रदेश का भौगोलिक आकार इतना बड़ा था कि एक ही केंद्र से समस्त क्षेत्रों का संतुलित विकास करना चुनौतीपूर्ण हो गया था। छत्तीसगढ़ को एक पृथक राज्य बनाकर, सरकार ने वहां की स्थानीय समस्याओं और संसाधनों के प्रबंधन हेतु एक केंद्रित प्रशासनिक ढांचा प्रदान किया। इस कदम का मुख्य लक्ष्य नौकरशाही की जटिलताओं को न्यून करना और क्षेत्रीय आकांक्षाओं के अनुरूप विकास कार्यों को गति प्रदान करना था। इस प्रकार, विभाजन का मुख्य आधार शासन की सुगमता और सामाजिक-आर्थिक प्रगति था।

270. (A) राज्य; सरकार
मध्य प्रदेश की संसदीय शासन प्रणाली में राज्यपाल और मुख्यमंत्री के मध्य शक्तियों का एक स्पष्ट और व्यवस्थित विभाजन है। राज्यपाल राज्य के औपचारिक प्रमुख होते हैं जो संपूर्ण 'राज्य' की निरंतरता, गरिमा और संवैधानिक सर्वोच्चता का प्रतिनिधित्व करते हैं; उनके नाम पर ही समस्त आधिकारिक कार्य संचालित होते हैं। इसके विपरीत, मुख्यमंत्री निर्वाचित 'सरकार' के वास्तविक प्रमुख होते हैं जो शासन की नीतियों का निर्माण करते हैं और दैनिक प्रशासन का नेतृत्व करते हैं। राज्यपाल का पद एक तटस्थ अभिभावक जैसा है, जबकि मुख्यमंत्री का पद सक्रिय कार्यकारी नेतृत्व का। यह संतुलन सुनिश्चित करता है कि राज्य का संवैधानिक ढांचा बना रहे और कार्यकारी शक्तियाँ जनता के प्रति जवाबदेह निर्वाचित नेतृत्व के पास रहें।

Downloaded from www.pdf.tube

अवसर प्रदान करती है। चुनाव प्रचार, घोषणापत्रों की प्रस्तुति और मतदान के माध्यम से होने वाली यह प्रतिस्पर्धा ही राज्य की लोकतांत्रिक व्यवस्था की आधारशिला है। यहाँ सत्ता का परिवर्तन शांतिपूर्ण और विधिसम्मत रीति से संभव होता है।

225. (A) इसकी भौगोलिक, आर्थिक और जनसांख्यिकीय विशेषताओं का पुनर्निर्धारण हुआ।
वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश का विभाजन केवल एक प्रशासनिक कदम नहीं था, अपितु इसने राज्य के मूल स्वरूप को ही परिवर्तित कर दिया। इस विभाजन के कारण मध्य प्रदेश ने अपनी भौगोलिक सीमाओं का एक विशाल भाग छत्तीसगढ़ को प्रदान किया, जिससे इसकी प्राकृतिक संपदा और जनसांख्यिकीय संरचना में बड़ा परिवर्तन आया। खनिज समृद्ध क्षेत्रों और सघन वन क्षेत्रों के छत्तीसगढ़ में चले जाने के कारण मध्य प्रदेश की आर्थिक नीतियों में कृषि और सेवा क्षेत्र की ओर झुकाव बढ़ा। साथ ही, विधानसभा की सीटों और प्रशासनिक ढांचे का भी पुनर्गठन हुआ। यह घटना आधुनिक मध्य प्रदेश के निर्माण में एक अत्यंत प्रभावशाली और निर्णायक मोड़ सिद्ध हुई।

226. (A) मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश।
यदि मध्य प्रदेश के राज्यपाल का पद उनके त्यागपत्र, निधन या किसी अन्य कारण से आकस्मिक रूप से रिक्त हो जाता है, तो राज्य में संवैधानिक शून्यता को रोकने हेतु एक विशेष व्यवस्था की गई है। ऐसी स्थिति में, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में पदभार ग्रहण करते हैं और राज्यपाल की समस्त शक्तियों और कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। यदि मुख्य न्यायाधीश भी उपलब्ध न हों, तो उच्च न्यायालय के सर्वाधिक वरिष्ठ न्यायाधीश इस उत्तरदायित्व को संभालते हैं। यह अंतरिम व्यवस्था तब तक बनी रहती है जब तक कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा नए राज्यपाल की स्थायी नियुक्ति नहीं कर दी जाती।

227. (A) मुख्यमंत्री द्वारा, संवैधानिक सीमाओं के अधीन।
मध्य प्रदेश में मंत्रिपरिषद का वास्तविक स्वरूप और उसका आकार मुख्यमंत्री द्वारा निर्धारित किया जाता है। मुख्यमंत्री ही यह निश्चित करते हैं कि उनकी टीम में कितने मंत्री होंगे और किसे कौन सा विभाग आवंटित किया जाएगा। यद्यपि, मुख्यमंत्री की यह शक्ति असीमित नहीं है; उन्हें 91वें संविधान संशोधन द्वारा निर्धारित सीमा का अनुपालन करना होता है, जिसके अनुसार मंत्रियों की कुल संख्या विधानसभा सीटों के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती। राज्यपाल केवल मुख्यमंत्री की अनुशंसा पर मंत्रियों की औपचारिक नियुक्ति और शपथ दिलाने का कार्य करते हैं। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि कार्यपालिका का नेतृत्व मुख्यमंत्री के पास प्रभावी रूप से बना रहे।

228. (A) राज्य का वार्षिक बजट पारित करना।
मध्य प्रदेश विधानसभा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण शक्तियों में से एक राज्य की वित्तीय व्यवस्था पर नियंत्रण बनाए रखना है। विधानसभा के पास वार्षिक बजट को पारित करने का अनन्य अधिकार है, जिसके बिना सरकार राज्य की संचित निधि से कोई भी व्यय नहीं कर सकती। बजट पर चर्चा और अनुदान मांगों को स्वीकृति प्रदान करना विधानसभा का एक प्रमुख विधायी कार्य है जो कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करता है। विदेश नीति और राज्यपाल की नियुक्ति जैसे प्रकरण केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, जबकि बजट पारित करना सीधे तौर पर राज्य की प्रगति और शासन को प्रभावित करने वाली सर्वोच्च विधायी शक्ति है।

229. (A) कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं।
मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष के पास कई महत्वपूर्ण विधायी शक्तियां हैं, जिनमें से सर्वाधिक प्रभावशाली किसी विधेयक को "धन विधेयक" के रूप में प्रमाणित करने की उनकी अनन्य शक्ति है। यदि किसी विधेयक के स्वरूप को लेकर कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो अध्यक्ष का यह निर्णय कि वह धन विधेयक है या नहीं, अंतिम और सर्वोपरी माना जाता है। इस निर्णय को किसी भी न्यायालय, राज्यपाल या स्वयं सदन द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती। यह प्रमाणीकरण अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि धन विधेयक पारित करने की प्रक्रिया साधारण विधेयकों की तुलना में अधिक तीव्र और विशिष्ट होती है, जो कार्यपालिका को वित्तीय सुगमता प्रदान करती है।

230. (A) A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या है।
मध्य प्रदेश की चुनावी राजनीति में जातिगत समीकरण एक गहरे और प्रभावशाली कारक के रूप में कार्य करते हैं। मतदाता अक्सर अपनी सामाजिक पहचान और सामुदायिक हितों की सुरक्षा हेतु अपनी जाति से संबद्ध उम्मीदवारों या दलों को प्राथमिकता प्रदान करते हैं। राजनीतिक दल भी इस वास्तविकता को समझते हुए, उम्मीदवारों के चयन और चुनावी प्रचार की रणनीतियों में जातिगत गणित का सूक्ष्म विश्लेषण करते हैं। किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र में बहुसंख्यक जाति के उम्मीदवार को टिकट देना एक सामान्य चुनावी रणनीति बन गई है। यह सामाजिक वास्तविकता राज्य के मतदान व्यवहार और सत्ता के वितरण को काफी सीमा तक निर्देशित और प्रभावित करती है।

231. (A) विशाल भौगोलिक क्षेत्र और प्रशासनिक चुनौतियाँ।
वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ के पृथक होने से पूर्व, अविभाजित मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विशालतम राज्य था। इसकी सीमाओं का विस्तार इतना व्यापक था कि इसे "विशाल राज्य" के रूप में पहचाना जाता था। इस विशालता के कारण ही इसे प्रशासनिक रूप से प्रबंधित करना एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि राजधानी भोपाल से दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों की दूरी अत्यधिक थी। इस बड़े भू-भाग में विविध संस्कृतियाँ, भाषाएं और भौगोलिक विशेषताएं सम्मिलित थीं। इसी प्रशासनिक जटिलता और क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने हेतु अंततः लघु और अधिक प्रबंधनीय राज्यों के निर्माण की आवश्यकता अनुभव की गई और विभाजन संपन्न हुआ।

232. (A) छह सप्ताह
संविधान के अनुच्छेद 213 के तहत, मध्य प्रदेश के राज्यपाल द्वारा जारी किया गया कोई भी अध्यादेश एक अस्थायी कानून की भांति कार्य करता है। जब राज्य विधानसभा का सत्र पुनः

NODIA

प्रारंभ होता है, तो उस अध्यादेश को सदन के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है। विधानसभा के पुनः समवेत होने की तिथि से छह सप्ताह की अवधि के भीतर यदि सदन उस अध्यादेश को अपनी स्वीकृति या अनुमोदन प्रदान नहीं करता है, तो वह स्वतः ही निष्प्रभावी और शून्य हो जाता है। यह समय सीमा सुनिश्चित करती है कि कार्यपालिका की विधायी शक्तियों पर निर्वाचित विधायिका का अंतिम और प्रभावी नियंत्रण बना रहे, जिससे लोकतांत्रिक मर्यादा सुरक्षित रहती है।

233. (A) राज्यपाल
मध्य प्रदेश में 'व्यक्तिगत उत्तरदायित्व' के संवैधानिक सिद्धांत के अनुसार, प्रत्येक मंत्री राज्य के राज्यपाल के प्रसादपर्यंत अपना पद धारण करता है। इसका विधिक अर्थ यह है कि राज्यपाल किसी भी समय किसी मंत्री को पदमुक्त कर सकते हैं। यद्यपि, संसदीय परंपराओं के अंतर्गत राज्यपाल इस शक्ति का प्रयोग केवल मुख्यमंत्री के परामर्श पर ही करते हैं। यदि मुख्यमंत्री किसी मंत्री के कार्य से संतुष्ट नहीं हैं या उन्हें अपनी टीम से विमुक्त करना चाहते हैं, तो वे राज्यपाल को उसे हटाने की अनुशंसा करते हैं। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक एकजुट और अनुशासित टीम के रूप में कार्य करे।

234. (A) नवनिर्वाचित सदन की पहली बैठक की अध्यक्षता करना और सदस्यों को शपथ दिलाना।
मध्य प्रदेश विधानसभा के आम निर्वाचन के पश्चात, जब नया सदन प्रथम बार मिलता है, तो राज्यपाल एक 'सामयिक अध्यक्ष' की नियुक्ति करते हैं। सामयिक अध्यक्ष सामान्यतः सदन के सर्वाधिक वरिष्ठ सदस्यों में से एक होते हैं। उनकी मुख्य जिम्मेदारी नवनिर्वाचित विधायकों को पद की शपथ दिलाना और नए स्थायी अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया का संचालन करना है। एक बार जब स्थायी अध्यक्ष का निर्वाचन संपन्न हो जाता है, तो सामयिक अध्यक्ष का पद स्वतः ही समाप्त हो जाता है। यह एक महत्वपूर्ण अंतरिम भूमिका है जो नई विधानसभा के विधिसम्मत गठन और उसके विधायी कामकाज के प्रारंभ को सुनिश्चित करती है।

235. (A) 4, 1, 2, 3
मध्य प्रदेश की राजनीतिक और संवैधानिक व्यवस्था में शक्तियों का एक स्पष्ट पदानुक्रम विद्यमान है। सर्वाधिक ऊपर राज्यपाल होते हैं, जो राज्य के संवैधानिक प्रमुख और प्रथम नागरिक हैं। उनके पश्चात मुख्यमंत्री का स्थान आता है, जो सरकार के वास्तविक प्रमुख और कार्यकारी शक्ति के केंद्र होते हैं। प्रशासनिक और नीतिगत निर्णयों हेतु मुख्यमंत्री की टीम में कैबिनेट मंत्री द्वितीय स्तर पर होते हैं, जो महत्वपूर्ण विभागों का संचालन करते हैं। अंत में राज्य मंत्री आते हैं, जो कैबिनेट मंत्रियों की सहायता करते हैं या लघु विभागों का स्वतंत्र प्रभार संभालते हैं। यह संरचना राज्य प्रशासन में उत्तरदायित्व को स्पष्ट करती है।

236. (A) भारत के राष्ट्रपति को
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की स्वतंत्रता और उनके पद की गरिमा को सुरक्षित रखने हेतु उनके त्यागपत्र की प्रक्रिया को उच्च स्तरीय बनाया गया है। यद्यपि वे राज्य के उच्च न्यायालय में कार्यरत होते हैं और राज्यपाल उन्हें शपथ दिलाते हैं, किंतु चूंकि उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, इसलिए वे अपना त्यागपत्र भी सीधे राष्ट्रपति को ही संबोधित करते हैं। राष्ट्रपति को पत्र प्रेषित करने के पश्चात ही उनका त्यागपत्र विधिसम्मत माना जाता है। इस प्रक्रिया में राज्य के राज्यपाल या मुख्यमंत्री की कोई आधिकारिक भूमिका नहीं होती है, जो न्यायपालिका के संघीय स्वरूप को प्रदर्शित करता है।

237. (D) अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस
मध्य प्रदेश की चुनावी राजनीति और इतिहास मुख्य रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के चारों ओर केंद्रित रहा है। ये दोनों दल दशकों से राज्य की सत्ता और विपक्ष में निरंतर सक्रिय रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी की भी राज्य के कुछ विशिष्ट क्षेत्रों, विशेषकर उत्तर प्रदेश से संलग्न सीमाओं वाले जिलों में, एक लघु किंतु निरंतर उपस्थिति और प्रभाव रहा है। इसके विपरीत, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल की क्षेत्रीय राजनीति तक सीमित है और मध्य प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य या चुनावी इतिहास में उसकी कोई उल्लेखनीय उपस्थिति या भूमिका कभी नहीं रही है।

238. (A) एकीकरण
1956 में मध्य प्रदेश का गठन भारतीय इतिहास में 'एकीकरण' की एक विशाल प्रक्रिया का परिणाम था। इस ऐतिहासिक कदम के माध्यम से भाषाई और प्रशासनिक आधार पर कई भिन्न-भिन्न राजनीतिक इकाइयों को संयोजित किया गया। इसमें पूर्ववर्ती मध्य प्रांत एवं बरार के हिंदी भाषी क्षेत्र, मध्य भारत की रियासतें, विंध्य प्रदेश और भोपाल राज्य का विलय किया गया ताकि एक सुदृढ़ और भौगोलिक रूप से सुगठित हिंदी भाषी राज्य का निर्माण हो सके। इस एकीकरण ने न केवल प्रशासनिक जटिलताओं को न्यून किया, अपितु विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों को एक साझा राजनीतिक पहचान के अंतर्गत लाकर राज्य के संतुलित विकास का मार्ग प्रशस्त किया।

239. (A) एकसदनीय विधायिका की परंपरा।
मध्य प्रदेश की राजव्यवस्था की एक प्रमुख और निरंतर विशेषता इसकी एकसदनीय विधायी संरचना है। इसका अर्थ है कि यहाँ राज्य विधायिका में केवल एक ही सदन, 'विधानसभा' विद्यमान है और विधान परिषद जैसी किसी द्वितीय संस्था का अस्तित्व नहीं है। यह संरचना विधायी प्रक्रिया को अधिक त्वरित, सरल और कम व्ययकारी बनाती है। यद्यपि संविधान में विधान परिषद निर्मित करने का प्रावधान है, किंतु मध्य प्रदेश ने सदैव ही एक ही निर्वाचित सदन के माध्यम से शासन करने की परंपरा को बनाए रखा है। यह सुनिश्चित करता है कि राज्य की समस्त विधायी शक्तियाँ सीधे जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास ही केंद्रित रहें।

240. (A) राज्य सरकार की नीति का एक विवरण।
मध्य प्रदेश विधानसभा में वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में राज्यपाल का अभिभाषण एक अत्यंत महत्वपूर्ण संवैधानिक परंपरा और दस्तावेज है। संविधान के अनुच्छेद 176 के तहत

Click Here to Buy book on Amazon

प्रदान किया जाने वाला यह भाषण वास्तव में राज्य की निर्वाचित सरकार द्वारा तैयार किया जाता है। इसमें सरकार की विगत उपलब्धियों का विवरण और आगामी वर्ष हेतु प्रस्तावित नीतियों, कार्यक्रमों और विधायी प्राथमिकताओं का विस्तृत विवरण होता है। राज्यपाल केवल सरकार के मुखपत्र के रूप में इस नीतिगत वक्तव्य को सदन के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। यह अभिभाषण सरकार के विजन को सार्वजनिक करने और उस पर सदन में व्यापक चर्चा का आधार बनता है।

241. (A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
मध्य प्रदेश की कार्यकारी व्यवस्था संसदीय लोकतंत्र के सिद्धांतों पर आधारित है, जहाँ शक्तियों का विभाजन नाममात्र और वास्तविक नेतृत्व के मध्य होता है। राज्यपाल राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं, जिनके नाम से प्रशासन के समस्त औपचारिक कार्य किए जाते हैं, जो उन्हें गरिमा और निरंतरता का प्रतीक बनाता है। दूसरी ओर, मुख्यमंत्री कार्यपालिका के वास्तविक प्रमुख होते हैं जो शासन की नीतियों का निर्माण करते हैं और प्रशासन का सक्रिय नेतृत्व करते हैं। राज्यपाल प्रायः मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के परामर्श पर ही अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। यह दोहरी व्यवस्था राज्य शासन में स्थिरता और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करती है।

242. (B) केवल 2 और 3
मध्य प्रदेश विधानसभा के पास महत्वपूर्ण विधायी और राजनीतिक शक्तियां हैं। यह राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत वार्षिक बजट पर चर्चा कर सकती है और उसमें संशोधन या कटौती प्रस्ताव ला सकती है, जो सरकार पर वित्तीय नियंत्रण का मुख्य साधन है। इसके अतिरिक्त, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही राज्य का प्रतिनिधित्व करने हेतु राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन करते हैं। यद्यपि, विधानसभा संघ सूची के विषयों पर कानून नहीं निर्मित कर सकती, क्योंकि उन पर अनन्य अधिकार भारत की संसद का है। विधानसभा केवल राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों तक ही सीमित रहती है, जो शक्तियों के वितरण को दर्शाता है।

243. (A) मत बराबर होने की स्थिति को तोड़ने के लिए।
मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष की भूमिका सदन में एक निष्पक्ष संचालक की होती है, इसलिए वे सामान्य मतदान में भाग नहीं लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 189 के तहत उन्हें 'निर्णायक मत' का अधिकार केवल तब प्राप्त होता है जब किसी विधेयक या प्रस्ताव पर सदन के सदस्यों के मत पूर्णतः बराबर-बराबर विभाजित हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में अध्यक्ष अपने मत का प्रयोग करके गतिरोध को समाप्त करते हैं और विषय का अंतिम निर्णय करते हैं। उनका यह मत व्यक्तिगत पसंद के स्थान पर विधायी प्रक्रिया को अग्रसर करने हेतु एक आवश्यक संवैधानिक उपकरण के रूप में कार्य करता है। यह व्यवस्था उनकी तटस्थता को सुरक्षित रखती है।

244. (A) इसके निर्णय शाश्वत स्मृति के लिए सुरक्षित रखे जाते हैं और उनका साक्ष्य मूल्य होता है।
संविधान के अनुच्छेद 215 के अनुसार, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय को एक 'अभिलेख न्यायालय' का दर्जा प्राप्त है। इसके दो मुख्य अर्थ हैं: प्रथम, इसके द्वारा प्रदान किए गए समस्त निर्णय और कार्यवाहियां स्थायी अभिलेख के रूप में सुरक्षित रखी जाती हैं, जिन्हें भविष्य में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा नजीर या साक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। द्वितीय, उच्च न्यायालय के पास अपनी अवमानना हेतु दंडित करने की विशेष शक्ति होती है। यह दर्जा न्यायालय के आदेशों की सर्वोच्चता और विश्वसनीयता को बनाए रखता है, जिससे राज्य की न्याय व्यवस्था में एकरूपता और स्थिरता सुनिश्चित होती है।

245. (A) राज्य विधानसभा और लोकसभा।
मध्य प्रदेश की चुनावी राजनीति में दो प्रकार के मुख्य प्रत्यक्ष निर्वाचन सम्मिलित होते हैं जो राज्य और केंद्र की शासन व्यवस्था को निर्धारित करते हैं। प्रथम विधानसभा निर्वाचन होते हैं, जहाँ मतदाता राज्य सरकार के गठन हेतु अपने स्थानीय विधायकों का निर्वाचन करते हैं। द्वितीय लोकसभा निर्वाचन होते हैं, जिनके माध्यम से राज्य के प्रतिनिधि भारतीय संसद के निचले सदन में जाते हैं और केंद्र सरकार के निर्माण में भाग लेते हैं। ये निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियमित अंतराल पर कराए जाते हैं। ये दोनों निर्वाचन राज्य के नागरिकों को राजनीतिक पसंद व्यक्त करने का अवसर प्रदान करते हैं।

246. (A) प्रशासनिक और विकासात्मक चिंताएं
वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश का विभाजन मुख्य रूप से प्रशासनिक सुगमता और संतुलित क्षेत्रीय विकास के उद्देश्यों से प्रेरित था। तत्कालीन राज्य का विशाल भौगोलिक आकार भोपाल से दूरस्थ छत्तीसगढ़ जैसे क्षेत्रों के कुशल प्रबंधन में बाधा उत्पन्न कर रहा था। विकास की क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने और जनजातीय बहुल क्षेत्रों की स्थानीय आकांक्षाओं को पूर्ण करने हेतु एक लघु और अधिक केंद्रित राज्य की मांग की गई थी। इस विभाजन का आधार भाषाई या धार्मिक नहीं था, अपितु यह शासन की पहुंच को जनता के समीप ले जाने और संसाधनों के बेहतर उपयोग हेतु किया गया एक सुविचारित प्रशासनिक निर्णय था।

247. (A) मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
भारत के संविधान के अनुच्छेद 159 के तहत, मध्य प्रदेश के राज्यपाल को उनके पद की शपथ राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। यदि मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हों, तो उच्च न्यायालय के उपलब्ध सर्वाधिक वरिष्ठ न्यायाधीश यह उत्तरदायित्व निर्वहन करते हैं। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान राज्यपाल संविधान के संरक्षण, परिरक्षण और प्रतिरक्षण की प्रतिज्ञा लेते हैं। यह एक महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रक्रिया है जिसके बिना राज्यपाल अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन प्रारंभ नहीं कर सकते। यह प्रक्रिया राज्य की न्यायपालिका और कार्यकारी प्रमुख के मध्य के औपचारिक संबंध और निष्ठा को प्रदर्शित करती है।

248. (A) मुख्यमंत्री की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा।
मध्य प्रदेश में मंत्रिपरिषद के गठन की प्रक्रिया संसदीय लोकतंत्र के नियमों का अनुपालन करती है। यद्यपि मंत्रियों की

201. (A) भारत के मुख्य न्यायाधीश और मध्य प्रदेश के राज्यपाल।
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में कई संवैधानिक संस्थाओं का सहयोग सम्मिलित होता है। संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श करते हैं। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रकरण में, वे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श लेते हैं। यह बहु-स्तरीय परामर्श प्रणाली यह सुनिश्चित करने हेतु निर्मित की गई है कि न्यायिक पदों पर नियुक्तियाँ पूर्णतः योग्यता और निष्पक्षता पर आधारित हों। यह प्रक्रिया न्यायपालिका की स्वतंत्रता और राज्य के प्रति उसके उत्तरदायित्व के मध्य संतुलन स्थापित करती है।

202. (A) दो राष्ट्रीय दलों का प्रभुत्व।
मध्य प्रदेश की दलीय व्यवस्था की सर्वाधिक प्रमुख विशेषता यहाँ भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसे दो विशाल राष्ट्रीय दलों का निरंतर वर्चस्व है। राज्य में चुनावी मुकाबला मुख्य रूप से इन्हीं दो दलों के मध्य केंद्रित रहता है, जिससे यहाँ की राजनीति एक स्पष्ट द्विध्रुवीय स्वरूप ग्रहण करती है। यद्यपि कुछ क्षेत्रों में लघु दल या निर्दलीय उम्मीदवार निर्वाचन लड़ते हैं, किंतु सरकार निर्माण और मुख्य विपक्ष की भूमिका में इन्हीं दो राष्ट्रीय दलों की प्रधानता रहती है। यह राजनीतिक ढांचा राज्य में गठबंधन सरकारों की आवश्यकता को न्यून करता है और स्पष्ट जनादेश वाली स्थिर सरकारों के गठन में सहायता प्रदान करता है।

203. (C) भोपाल
1 नवंबर, 1956 को जब नवीन मध्य प्रदेश का गठन हुआ, तब भोपाल को इसकी राजधानी के रूप में चुना गया। उस समय भोपाल एक पृथक भाग 'सी' राज्य था और इसकी केंद्रीय स्थिति तथा उपलब्ध प्रशासनिक बुनियादी ढांचे के कारण इसे राजधानी बनाना सर्वाधिक उपयुक्त समझा गया। यद्यपि उस समय जबलपुर और ग्वालियर जैसे अन्य विशाल नगर भी इस दौड़ में सम्मिलित थे, किंतु भोपाल की भौगोलिक स्थिति और ऐतिहासिक महत्व ने इसे यह गौरव प्रदान किया। तब से भोपाल राज्य की राजनीतिक, प्रशासनिक और विधायी गतिविधियों का मुख्य केंद्र बना हुआ है, जहाँ विधानसभा और सचिवालय जैसे समस्त प्रमुख संस्थान स्थित हैं।

204. (D) 1, 2 और 3
मध्य प्रदेश की राजनीतिक प्रणाली भारतीय संघीय ढांचे की विशेषताओं को प्रदर्शित करती है। यहाँ एकसदनीय विधायिका है, जिसका अर्थ है कि यहाँ केवल विधानसभा कार्य करती है। राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, जो केंद्र और राज्य के मध्य कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त, मध्य प्रदेश भारतीय संसद के दोनों सदनों में अपने प्रतिनिधि प्रेषित करता है, जिसमें 29 सदस्य लोकसभा हेतु और 11 सदस्य राज्यसभा हेतु निर्वाचित होते हैं। ये समस्त तत्व मिलकर राज्य की लोकतांत्रिक संरचना को पूर्ण करते हैं, जहाँ राज्य और केंद्र के मध्य शक्तियों का स्पष्ट और व्यवस्थित वितरण सुनिश्चित होता है।

205. (A) केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में।
मध्य प्रदेश के राज्यपाल की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण और 'दोहरी' प्रकृति की है। एक ओर वे राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं, जिनके नाम से राज्य का संपूर्ण प्रशासन संचालित होता है। दूसरी ओर, वे केंद्र सरकार के एक अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करते हैं। उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वे नियमित रूप से राज्य की राजनीतिक और प्रशासनिक स्थिति का विवरण केंद्र को प्रेषित करते हैं। यह दोहरी भूमिका संघीय ढांचे में केंद्र और राज्य के मध्य एक महत्वपूर्ण सेतु का कार्य करती है, जिससे राष्ट्रीय एकता और राज्य के शासन में संवैधानिक मर्यादा बनी रहती है।

206. (A) ब्रिटिश संसदीय प्रणाली।
मध्य प्रदेश में मंत्रिपरिषद का संगठन और उसकी कार्यप्रणाली पूर्णतः ब्रिटिश वेस्टमिंस्टर मॉडल या संसदीय प्रणाली पर आधारित है। इस व्यवस्था में कार्यपालिका (मंत्रिपरिषद) विधायिका (विधानसभा) का ही भाग होती है और उसके प्रति प्रत्यक्ष रूप से जवाबदेह होती है। मुख्यमंत्री सरकार के वास्तविक प्रमुख होते हैं जो सदन में बहुमत प्राप्त दल का नेतृत्व करते हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व और राज्यपाल की संवैधानिक प्रमुख के रूप में भूमिका इसी प्रणाली की देन है। यह मॉडल सुनिश्चित करता है कि सरकार सदैव निर्वाचित प्रतिनिधियों के विश्वास पर टिकी रहे, जो लोकतंत्र की एक सशक्त और पारदर्शी पहचान है।

207. (A) यह संविधान के उल्लंघन के लिए राज्यपाल पर महाभियोग चला सकती है।
मध्य प्रदेश विधानसभा के पास व्यापक विधायी शक्तियां हैं, जिनमें राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाना, बजट पारित करना और मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाना सम्मिलित है। यद्यपि, राज्यपाल पर महाभियोग चलाने की शक्ति विधानसभा के पास नहीं है। संविधान के अनुसार, राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करते हैं और उन्हें पद से विमुक्त करने का एकमात्र अधिकार राष्ट्रपति के पास ही सुरक्षित है। राज्यपाल किसी राज्य विधानसभा के प्रति नहीं, अपितु राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेह होते हैं। अतः महाभियोग की प्रक्रिया राज्यपाल हेतु प्रभावी नहीं होती, यह केवल राष्ट्रपति हेतु संसद में अपनाई जाती है।

208. (A) P-1, Q-4, R-2, S-3
मध्य प्रदेश की राजव्यवस्था को समझने हेतु इन चार महत्वपूर्ण संवैधानिक और राजनीतिक स्तंभों का ज्ञान आवश्यक है। द्विध्रुवीयता यहाँ की दलीय व्यवस्था की मुख्य पहचान है, जहाँ दो विशाल दलों के मध्य प्रतिस्पर्धा होती है। पुनर्गठन वह ऐतिहासिक प्रक्रिया है जिससे 1956 में राज्य की वर्तमान सीमाओं का निर्धारण हुआ। क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय की उन विधिक शक्तियों को परिभाषित करता है जिनके अंतर्गत वह न्याय प्रदान करता है। विवेकाधीन शक्ति राज्यपाल के उस विशेष अधिकार से संबंधित है जहाँ वे बिना मंत्रिपरिषद के

Downloaded from www.pdf.tube

256. (A) राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच मुख्य कड़ी।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की भूमिका राज्य के शासन तंत्र में एक धुरी की भांति है। वे न केवल मंत्रिपरिषद के नेता और वास्तविक कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं, अपितु राज्यपाल और कैबिनेट के मध्य संवाद का एकमात्र आधिकारिक माध्यम भी होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 167 के तहत, मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य है कि वे राज्य के प्रशासन और विधायी प्रस्तावों से संबंधित मंत्रिपरिषद के समस्त निर्णयों की सूचना राज्यपाल को प्रदान करें। राज्यपाल भी मुख्यमंत्री के माध्यम से ही किसी विशिष्ट प्रकरण पर जानकारी मांग सकते हैं। यह निरंतर संपर्क सुनिश्चित करता है कि राज्य के संवैधानिक और कार्यकारी प्रमुखों के मध्य समन्वय बना रहे।

257. (A) केवल 1 और 3
मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष का पद अत्यंत गरिमामयी और विधायी शक्तियों से परिपूर्ण है। अध्यक्ष का निर्वाचन सदन के नवनिर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने ही मध्य से किया जाता है, जो उनकी लोकतांत्रिक स्वीकार्यता को प्रदर्शित करता है। अध्यक्ष के पास किसी विधेयक को 'धन विधेयक' के रूप में प्रमाणित करने की विशेष और अंतिम शक्ति होती है, जिसे कहीं भी चुनौती नहीं दी जा सकती। यद्यपि, उन्हें हटाने की प्रक्रिया केवल साधारण बहुमत से नहीं, अपितु विधानसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के प्रभावी बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा ही संभव है। यह कठिन प्रक्रिया अध्यक्ष की स्वायत्तता और निष्पक्षता को सुरक्षित रखने हेतु अपनाई गई है।

258. (A) बजट पर बहस और कटौती प्रस्ताव।
मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के पास सरकार की वित्तीय नीतियों और व्यय पर नियंत्रण रखने हेतु 'कटौती प्रस्ताव' एक अत्यंत प्रभावी विधायी उपकरण है। बजट सत्र के दौरान, जब सरकार अनुदान मांगें प्रस्तुत करती है, तो विपक्षी सदस्य इन मांगों में न्यूनता करने हेतु नीति कटौती, मितव्ययिता कटौती या प्रतीक कटौती जैसे प्रस्ताव ला सकते हैं। इन प्रस्तावों पर होने वाली चर्चा के माध्यम से विपक्ष सरकारी धन के संभावित दुरुपयोग या त्रुटिपूर्ण वित्तीय प्राथमिकताओं को जनता के समक्ष लाता है। यह प्रक्रिया कार्यपालिका को वित्तीय मामलों में अधिक पारदर्शी और मितव्ययी बनाने हेतु बाध्य करती है, जो लोकतांत्रिक जवाबदेही का मुख्य आधार है।

259. (A) मध्य प्रदेश के भीतर अधीनस्थ न्यायालयों से।
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार उसे राज्य की संपूर्ण न्यायिक व्यवस्था के शीर्ष पर स्थापित करता है। इस शक्ति के तहत, उच्च न्यायालय राज्य के समस्त जिला अदालतों, सत्र न्यायालयों और विशिष्ट न्यायाधिकरणों के निर्णयों के विरुद्ध दीवानी और आपराधिक अपीलों की सुनवाई करता है। यदि किसी पक्ष को निचली अदालत के निर्णय में विधिक त्रुटि या अन्याय अनुभव होता है, तो वे उच्च न्यायालय का द्वार खटखटा सकते हैं। यह क्षेत्राधिकार सुनिश्चित करता है कि राज्य में कानून की व्याख्या एक समान हो और अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा की गई किसी भी न्यायिक चूक को समय पर सुधारा जा सके, जिससे न्याय की विश्वसनीयता बनी रहती है।

260. (A) दीर्घकालिक दलीय निष्ठा, अल्पकालिक मुद्दे और उम्मीदवार का प्रदर्शन।
मध्य प्रदेश में मतदाताओं का मतदान व्यवहार एक जटिल सामाजिक-राजनीतिक प्रक्रिया है जो कई कारकों के मिलन से प्रभावित होती है। एक ओर, कई परिवारों और समुदायों की किसी विशेष दल के प्रति 'दीर्घकालिक निष्ठा' होती है जो पीढ़ी-दर-पीढ़ी संचालित होती है। दूसरी ओर, निर्वाचन के समय उत्पन्न होने वाले 'अल्पकालिक मुद्दे' जैसे महंगाई, बेरोजगारी या कोई विशेष सरकारी योजना मतदाताओं के रुझान को परिवर्तित कर सकते हैं। इसके साथ ही, स्थानीय उम्मीदवार की छवि, उसकी पहुँच और विगत 'प्रदर्शन' भी व्यक्तिगत स्तर पर मतों को प्रभावित करता है। इन समस्त तत्वों का संतुलित प्रभाव ही अंततः राज्य के चुनावी परिणामों को निर्धारित करता है।

NODIA

261. (A) भारत का मध्य उच्च प्रदेश।
वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ के पृथक होने के पश्चात, मध्य प्रदेश का भौगोलिक केंद्र और भी अधिक स्पष्ट हो गया, जिससे यह मुख्य रूप से 'मध्य उच्च प्रदेश' का प्रतिनिधि राज्य बन गया। इस विभाजन ने राज्य को उसकी वर्तमान सीमाओं में समेटा, जहाँ विंध्य और सतपुड़ा की पर्वत श्रृंखलाएँ, मालवा का पठार और नर्मदा की घाटी इसके मुख्य भौगोलिक अंग बने। बिना किसी समुद्री तटरेखा या अंतरराष्ट्रीय सीमा के, यह राज्य अब पूर्णतः भारत के आंतरिक भाग में स्थित है। यह केंद्रीय स्थिति इसे देश के विभिन्न भागों के मध्य एक सांस्कृतिक और व्यापारिक सेतु के रूप में कार्य करने का अवसर प्रदान करती है, जो इसकी अर्थव्यवस्था और राजनीति को प्रभावित करती है।

262. (C) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
मध्य प्रदेश के राज्यपाल की पदच्युति के संबंध में भारतीय संविधान ने राष्ट्रपति को व्यापक और विवेकाधीन शक्तियां प्रदान की हैं। राज्यपाल का कोई निश्चित कार्यकाल सुरक्षा नहीं होती और राष्ट्रपति उन्हें किसी भी समय पद से विमुक्त कर सकते हैं, क्योंकि वे राष्ट्रपति के 'प्रसादपर्यंत' पद धारण करते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि संविधान में राज्यपाल को पद से हटाने हेतु न तो किसी विशिष्ट आधार का उल्लेख किया गया है और न ही किसी विस्तृत विधिक प्रक्रिया (जैसे महाभियोग) का प्रावधान है। यह व्यवस्था केंद्र सरकार को राज्य प्रशासन पर एक प्रभावी पर्यवेक्षी नियंत्रण प्रदान करती है, यद्यपि उच्चतम न्यायालय ने इसके राजनीतिक दुरुपयोग के विरुद्ध समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

263. (A) राज्यपाल
मध्य प्रदेश की संवैधानिक संरचना में मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद का यह प्राथमिक कर्तव्य है कि वे राज्य के राज्यपाल को उनके कार्यों के निर्वहन में सहायता और परामर्श प्रदान करें। संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत यह एक अनिवार्य व्यवस्था है, क्योंकि राज्यपाल राज्य के नाममात्र के प्रमुख हैं और वे वास्तविक कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद के इसी परामर्श के आधार पर ही करते हैं। यद्यपि कुछ प्रकरणों में राज्यपाल को विवेकाधीन शक्तियां प्राप्त हैं, किंतु सामान्य प्रशासन और विधायी कार्यों में वे मंत्रिपरिषद के परामर्श के

सीमाओं से बाहर जाकर कार्य न करे। न्यायिक पुनरावलोकन लोकतंत्र में कानून के शासन और संवैधानिक सर्वोच्चता को बनाए रखने का एक अनिवार्य साधन है।

217. (A) कुछ क्षेत्रों में छोटे दलों का महत्वपूर्ण लेकिन सीमित प्रभाव।
मध्य प्रदेश की दलीय व्यवस्था यद्यपि मुख्य रूप से द्विध्रुवीय है और भारतीय जनता पार्टी व कांग्रेस के वर्चस्व वाली है, किंतु इसका एक अन्य आयाम भी महत्वपूर्ण है। राज्य के कुछ विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों, जैसे ग्वालियर-चंबल और बुंदेलखंड के कुछ भागों में, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी जैसे लघु दलों का एक निश्चित और प्रभावी जनाधार है। ये दल भले ही संपूर्ण राज्य में सरकार निर्माण की स्थिति में न हों, किंतु वे त्रिकोणीय मुकाबला निर्मित कर बड़े दलों के चुनावी गणित को प्रभावित करने और गठबंधन की संभावनाओं को जन्म देने की क्षमता रखते हैं। यह विविधता राज्य की राजनीति को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाती है।

218. (B) भाग A, B और C राज्य
1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम से पूर्व, भारत में राज्यों को उनके प्रशासनिक और ऐतिहासिक आधार पर भाग ए, बी, सी और डी की श्रेणियों में विभाजित किया गया था। इस वर्गीकरण को 1956 के ऐतिहासिक सुधार के माध्यम से पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। इसके स्थान पर, भाषाई और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर एक समान राज्य प्रणाली अपनाई गई। मध्य प्रदेश का गठन भी इसी सुधार का परिणाम था, जिसमें पूर्ववर्ती भाग 'ए' के मध्य प्रांत, भाग 'बी' के मध्य भारत और भाग 'सी' के विंध्य प्रदेश व भोपाल का विलय किया गया। इस कदम ने भारतीय संघीय ढांचे को एक सरल और अधिक व्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया।

219. (A) कृषि संबंधी मुद्दे और किसान कल्याण
मध्य प्रदेश की अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और आजीविका हेतु मुख्य रूप से कृषि पर आश्रित है, इसलिए कृषि संबंधी मुद्दे यहाँ की राजनीति का केंद्र बिंदु रहे हैं। सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य, खाद और बीज की उपलब्धता तथा ऋण मुक्ति जैसे विषय चुनावी विमर्श को गहराई से प्रभावित करते हैं। राजनीतिक दल कृषकों के कल्याण हेतु विभिन्न योजनाओं और वादों के माध्यम से मतदाताओं को आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। राज्य की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान होने के कारण, कोई भी सरकार इन मुद्दों की उपेक्षा करने का जोखिम नहीं ले सकती है।

220. (A) जब चुनाव के परिणामस्वरूप त्रिशंकु विधानसभा बनती है।
मध्य प्रदेश के राज्यपाल सामान्यतः मुख्यमंत्री के परामर्श पर कार्य करते हैं, किंतु 'त्रिशंकु विधानसभा' की स्थिति उनके विवेक की परीक्षा होती है। जब किसी भी दल या गठबंधन को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता, तब राज्यपाल को यह निश्चित करना होता है कि किसे सरकार निर्माण हेतु आमंत्रित किया जाए। इस परिस्थिति में वे अपनी विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए उस नेता का चयन करते हैं जो सदन में एक स्थिर सरकार प्रदान करने की सर्वाधिक संभावना रखता हो। यह निर्णय पूर्णतः राज्यपाल के विवेक पर निर्भर करता है और यह राज्य की राजनीतिक स्थिरता हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण और निर्णायक क्षण होता है।

221. (A) मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करना।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के वास्तविक प्रमुख और इसकी धुरी होते हैं। उनकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिकाओं में से एक मंत्रिमंडल की बैठकों का आयोजन करना और उनकी अध्यक्षता करना है। इन बैठकों में राज्य की समस्त प्रमुख नीतियों, विधायी प्रस्तावों और प्रशासनिक निर्णयों पर चर्चा की जाती है और उन्हें अंतिम रूप प्रदान किया जाता है। मुख्यमंत्री ही यह सुनिश्चित करते हैं कि सरकार एक संगठित इकाई के रूप में कार्य करे और समस्त मंत्री सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का अनुपालन करें। यद्यपि सत्र बुलाना राज्यपाल की शक्ति है, किंतु प्रशासन का वास्तविक नेतृत्व मुख्यमंत्री के हाथ में ही रहता है।

222. (A) केवल 1 और 3
मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष की भूमिका एक सशक्त प्रहरी की होती है। इसे 'वैकल्पिक सरकार' कहा जाता है क्योंकि यह किसी भी समय शासन की त्रुटियों को उजागर कर सत्ता संभालने हेतु तत्पर रहती है। विपक्ष प्रश्नकाल, शून्यकाल और विभिन्न प्रस्तावों जैसे विधायी उपकरणों का प्रयोग करके सरकार के प्रत्येक निर्णय और वित्तीय व्यय की सूक्ष्म जांच करता है। सरकार की प्रशंसा करना विपक्ष का कार्य नहीं है, अपितु रचनात्मक आलोचना के माध्यम से शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। एक सक्रिय विपक्ष ही यह सुनिश्चित करता है कि कार्यपालिका सदैव सचेत रहे और जनहित के कार्यों में प्रमाद न बरते।

223. (A) मध्य प्रदेश का संपूर्ण राज्य।
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र भौगोलिक रूप से संपूर्ण मध्य प्रदेश राज्य की सीमाओं तक विस्तृत है। इसका अर्थ है कि राज्य के भीतर होने वाले समस्त विधिक विवाद, अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील और नागरिकों के मौलिक अधिकारों के हनन से संबद्ध प्रकरण इसी उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। यद्यपि छत्तीसगढ़ पूर्व में मध्य प्रदेश का भाग था, किंतु 2000 में विभाजन के पश्चात बिलासपुर में एक पृथक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। वर्तमान में, जबलपुर स्थित मुख्य पीठ और खंडपीठों के माध्यम से यह न्यायालय संपूर्ण मध्य प्रदेश में न्याय प्रशासन की सर्वोच्च निगरानी करता है।

224. (A) चुनावी प्रक्रिया।
मध्य प्रदेश में राजनीतिक शक्ति प्राप्ति का एकमात्र और सर्वोपरि माध्यम स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया है। प्रमुख राजनीतिक दल जैसे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, नियमित अंतराल पर होने वाले विधानसभा निर्वाचनों के माध्यम से जनता का जनादेश प्राप्त करने की प्रतिस्पर्धा करते हैं। यह प्रक्रिया मतदाताओं को अपने प्रतिनिधियों को चुनने और अपनी पसंदीदा विचारधारा वाली सरकार निर्मित करने का

Click Here to Buy book on Amazon

271. (A) राज्यपाल
मध्य प्रदेश में मंत्रिपरिषद के सदस्य व्यक्तिगत रूप से राज्य के राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसका संवैधानिक अभिप्राय यह है कि प्रत्येक मंत्री राज्यपाल के 'प्रसादपर्यंत' अपना पद धारण करता है। यदि राज्यपाल किसी मंत्री को पद से विमुक्त करना चाहें, तो वे ऐसा कर सकते हैं, यद्यपि व्यावहारिक रूप से यह शक्ति केवल मुख्यमंत्री के परामर्श पर ही प्रयुक्त की जाती है। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का यह सिद्धांत सामूहिक उत्तरदायित्व से भिन्न है, क्योंकि यह प्रत्येक मंत्री की राज्यपाल और मुख्यमंत्री के प्रति निष्ठा और जिम्मेदारी सुनिश्चित करता है। यह व्यवस्था मुख्यमंत्री को अपनी टीम में अनुशासन बनाए रखने और आवश्यकतानुसार मंत्रियों के विभागों में परिवर्तन या उन्हें हटाने की शक्ति प्रदान करती है।

272. (A) P-3, Q-1, R-2, S-3
मध्य प्रदेश की विधायी और कार्यकारी प्रक्रियाओं में विभिन्न अधिकारियों की भूमिकाएँ स्पष्ट रूप से परिभाषित हैं। राज्यपाल के पास विधानसभा को भंग करने और बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करने की महत्वपूर्ण संवैधानिक शक्तियां होती हैं। विधानसभा एक सामूहिक निकाय के रूप में राज्य का वार्षिक बजट पारित करने की सर्वोच्च वित्तीय शक्ति रखती है, जिसके बिना सरकारी व्यय संभव नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष का मुख्य कार्य सदन की दैनिक बैठकों का संचालन करना और व्यवस्था बनाए रखने हेतु बैठकों को स्थगित करना है। ये समस्त प्राधिकारी मिलकर राज्य के लोकतांत्रिक ढांचे को सुचारू रूप से संचालित करते हैं, जहाँ प्रत्येक कार्य हेतु एक विशिष्ट और उत्तरदायी पद निर्धारित किया गया है।

273. (A) नीतियों में कमियां बताकर और विकल्प सुझाकर।
लोकतंत्र में विपक्षी दलों की भूमिका केवल विरोध करना नहीं, अपितु शासन में 'रचनात्मक सुधार' लाना है। विपक्ष एक सतर्क प्रहरी की भांति कार्य करता है जो सरकार द्वारा प्रस्तावित कानूनों और नीतियों की सूक्ष्म समीक्षा करता है और उनमें छिपी हुई त्रुटियों या जनविरोधी प्रावधानों को उजागर करता है। केवल आलोचना करने के स्थान पर, एक परिपक्व विपक्ष श्रेष्ठ विकल्प और सुझाव भी प्रस्तुत करता है कि कैसे किसी योजना को अधिक प्रभावी और जन-हितैषी बनाया जा सकता है। यह प्रक्रिया सरकार को अपनी त्रुटियों को सुधारने हेतु प्रेरित करती है और यह सुनिश्चित करती है कि कानून निर्माण में केवल बहुमत की इच्छा ही नहीं, अपितु विभिन्न दृष्टिकोणों का भी सम्मान किया जाए।

274. (A) उनके आचरण पर महाभियोग प्रस्ताव को छोड़कर विधायिका में चर्चा नहीं की जा सकती।
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की न्यायिक स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने हेतु संविधान में कई कठोर प्रावधान किए गए हैं। इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण यह है कि किसी भी न्यायाधीश के न्यायिक आचरण या उनके द्वारा प्रदान किए गए निर्णयों पर राज्य विधानसभा में कोई चर्चा नहीं की जा सकती। इस नियम का एकमात्र अपवाद तब होता है जब संसद में संबंधित न्यायाधीश को विमुक्त करने हेतु महाभियोग का प्रस्ताव विचाराधीन हो। यह निषेध सुनिश्चित करता है कि न्यायाधीश बिना किसी राजनीतिक दबाव, आलोचना के भय या विधायी हस्तक्षेप के पूर्ण निष्पक्षता और निर्भीकता के साथ न्याय कर सकें। यह सुरक्षा न्यायपालिका की स्वायत्तता और कानून के शासन को बनाए रखने हेतु अनिवार्य है।

275. (A) राज्य की विदेश व्यापार नीति
मध्य प्रदेश की चुनावी राजनीति और मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारकों में स्थानीय और राष्ट्रीय मुद्दे प्रमुख होते हैं। नेतृत्व का आकर्षण, जातिगत समीकरण और सरकार की विकास व कल्याणकारी योजनाएं प्रत्यक्ष रूप से सामान्य जनता के जीवन को प्रभावित करती हैं, इसलिए वे मतदान के दौरान निर्णायक भूमिका निर्वहन करते हैं। इसके विपरीत, चूंकि विदेश व्यापार और अंतरराष्ट्रीय संबंध पूर्णतः केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र के विषय हैं, इसलिए राज्य स्तर के निर्वाचनों में इनका प्रभाव नगण्य होता है। मतदाता सामान्यतः उन विषयों को प्राथमिकता प्रदान करते हैं जिनका उनके दैनिक जीवन और क्षेत्रीय प्रगति से सीधा संबंध हो, जिससे राज्य की विदेश व्यापार नीति मतदान व्यवहार का एक अत्यंत गौण कारक बन जाती है।

276. (A) भाषा के आधार पर भारत के राजनीतिक मानचित्र को पुनः निर्मित करना।
1956 में मध्य प्रदेश का गठन भारत की उस व्यापक लोकतांत्रिक आकांक्षा का परिणाम था जहाँ राज्यों की सीमाओं को प्रमुख भाषाओं के क्षेत्रों के साथ संयोजित करने की मांग की जा रही थी। इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य प्रशासन को जनता के अधिक समीप लाना और सांस्कृतिक समरूपता को प्रोत्साहित करना था। हिंदी भाषी विभिन्न रियासतों और प्रांतों को संयोजित कर एक संगठित राज्य निर्मित कर, सरकार ने शासन को भाषाई आधार पर अधिक सरल और सुलभ बनाने का प्रयास किया। यह पुनर्गठन केवल सीमाओं का परिवर्तन नहीं था, अपितु स्वतंत्र भारत के संघीय ढांचे को भाषाई और सांस्कृतिक विविधता के सम्मान के साथ व्यवस्थित करने की एक ऐतिहासिक और दूरदर्शी पहल थी।

277. (A) महत्वपूर्ण कृषि अर्थव्यवस्था और ग्रामीण जनसंख्या।
मध्य प्रदेश की सर्वाधिक विशिष्ट राजनीतिक और आर्थिक पहचान इसका कृषि प्रधान स्वरूप है। राज्य की एक बहुत विशाल आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और अपनी आजीविका हेतु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर आश्रित है। यह जनसांख्यिकीय संरचना राज्य के राजनीतिक कार्यसूची और चुनावी विमर्श को गहराई से प्रभावित करती है। कोई भी राजनीतिक दल कृषकों के हितों, ग्रामीण बुनियादी ढांचे और कृषि आधारित योजनाओं की उपेक्षा नहीं कर सकता। मध्य प्रदेश में ग्रामीण मतदाताओं की प्राथमिकताएँ ही सत्ता के समीकरणों को निर्धारित करती हैं, जो राज्य की राजनीति को एक ठोस ग्रामीण और कृषक-उन्मुख आधार प्रदान करती हैं।

278. (A) आंग्ल-भारतीय
भारतीय संविधान के पूर्व प्रावधानों के अनुसार, मध्य प्रदेश के राज्यपाल के पास यह विशेष शक्ति थी कि यदि उन्हें प्रतीत

Downloaded from www.pdf.tube

होता कि राज्य विधानसभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो वे उस समुदाय के एक सदस्य को सदन में नामांकित कर सकते थे। यह व्यवस्था इस लघु अल्पसंख्यक समुदाय की स्वर को विधायी प्रक्रिया में सम्मिलित करने हेतु की गई थी। यद्यपि, 104वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 के माध्यम से, अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण को तो विस्तारित किया गया, किंतु लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आंग्ल-भारतीयों के नामांकन की इस प्रथा को अब समाप्त कर दिया गया है। वर्तमान में मध्य प्रदेश विधानसभा के समस्त सदस्य केवल निर्वाचित प्रतिनिधि ही होते हैं।

279. (A) राज्य प्रशासन और नीति-निर्माण।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की वास्तविक शक्ति और प्रभाव का मुख्य क्षेत्र राज्य का आंतरिक प्रशासन और महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों का निर्माण है। वे मंत्रिपरिषद के प्रमुख के रूप में राज्य के विकास हेतु विजन तैयार करते हैं और स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि व कानून-व्यवस्था जैसे विषयों पर निर्णायक भूमिका निर्वहन करते हैं। नौकरशाही पर नियंत्रण और बजटीय आवंटन की प्राथमिकताओं को निश्चित करना उनकी कार्यकारी शक्ति के मुख्य अंग हैं। जबकि विदेश मामले और संसदीय निर्वाचन केंद्र के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, राज्य के भीतर मुख्यमंत्री ही शासन के वास्तविक सूत्रधार और जनता की आकांक्षाओं को पूर्ण करने वाले मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं। उनकी नीतियां ही राज्य की प्रगति की दिशा निश्चित करती हैं।

280. (A) मुख्य सचिव की नियुक्ति करके
मध्य प्रदेश विधानसभा कार्यपालिका की शक्तियों को नियंत्रित करने और उसकी जवाबदेही निश्चित करने हेतु कई प्रभावी विधायी उपकरणों का प्रयोग करती है। प्रश्नकाल, शून्यकाल, स्थगन प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से विधायक सरकार की नीतियों और कार्यों पर निरंतर दबाव बनाए रखते हैं और उनकी त्रुटियों को उजागर करते हैं। यद्यपि, मुख्य सचिव की नियुक्ति करना पूर्णतः कार्यपालिका अर्थात मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद का प्रशासनिक विशेषाधिकार है, जिसमें विधानसभा की कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं होती। मुख्य सचिव राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है, जिसका चयन सरकार द्वारा वरिष्ठता और योग्यता के आधार पर किया जाता है। विधानसभा केवल इस नियुक्ति में त्रुटियों पर प्रश्न उठा सकती है।

281. (A) संसदीय लोकतंत्र
संसदीय लोकतंत्र में विधानसभा अध्यक्ष का पद निष्पक्षता और सुचारु शासन का आधार स्तंभ माना जाता है। अध्यक्ष की भूमिका केवल सदन की बैठकों की अध्यक्षता करने तक सीमित नहीं है, अपितु वे सदन की गरिमा, सदस्यों के विशेषाधिकारों और विधायी नियमों के संरक्षक भी होते हैं। उनके बिना सदन की कार्यवाही का व्यवस्थित और न्यायसंगत संचालन असंभव है। अध्यक्ष सुनिश्चित करते हैं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को अपनी स्वर रखने का समान अवसर प्राप्त हो, जिससे लोकतांत्रिक विमर्श जीवंत बना रहता है। उनकी निष्पक्षता और निर्णय लेने की शक्ति ही विधायी प्रक्रिया की विश्वसनीयता और शुचिता को बनाए रखती है, जो संसदीय प्रणाली की सफलता हेतु अनिवार्य है।

282. (A) अभिलेख न्यायालय के रूप में इसकी शक्ति।
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का 'अभिलेख न्यायालय' होना उसे एक विशेष और सर्वोच्च विधिक दर्जा प्रदान करता है। इस शक्ति के तहत, न्यायालय के पास अपनी स्वयं की अवमानना हेतु किसी भी व्यक्ति या संस्था को दंडित करने का अनन्य अधिकार है। यह शक्ति इसलिए प्रदान की गई है ताकि न्यायालय के आदेशों और गरिमा का सम्मान बना रहे और कोई भी न्याय की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न न कर सके। इसके अतिरिक्त, एक अभिलेख न्यायालय के रूप में इसके समस्त निर्णयों को भविष्य के संदर्भों हेतु सुरक्षित रखा जाता है और वे राज्य की समस्त निचली अदालतों पर विधिक नजीर के रूप में बाध्यकारी होते हैं। यह शक्ति उच्च न्यायालय की न्यायिक संप्रभुता और प्रभावशीलता को सुनिश्चित करती है।

283. (A) प्रतिस्पर्धी विचारधाराओं वाले विभिन्न सामाजिक समूहों के व्यापक गठबंधन।
मध्य प्रदेश की राजनीति में प्रभावी रहने वाले प्रमुख दल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, केवल एक सीमित वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं करते, अपितु वे समाज के विभिन्न वर्गों, जातियों और हितों के 'व्यापक गठबंधन' के रूप में कार्य करते हैं। इन दोनों दलों की विचारधाराएं प्रतिस्पर्धी हैं, जहाँ एक ओर सामाजिक समावेश और धर्मनिरपेक्षता पर बल प्रदान किया जाता है, वहीं दूसरी ओर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और सुदृढ़ शासन पर। ये दल ग्रामीण कृषकों से लेकर शहरी मध्यम वर्ग तक और आदिवासियों से लेकर व्यापारियों तक के हितों को समाहित करने का प्रयास करते हैं। यह बहुआयामी प्रतिनिधित्व ही उन्हें राजनीतिक प्रभुत्व और सत्ता हेतु निरंतर संघर्ष करने की शक्ति प्रदान करता है।

284. (A) भौगोलिक रूप से सुगठित और भाषाई रूप से समरूप हों।
1956 के राज्यों के पुनर्गठन का मुख्य उद्देश्य भारत के प्रशासनिक मानचित्र को अधिक तर्कसंगत और कार्यात्मक निर्मित करना था। इसका लक्ष्य ऐसे राज्यों का निर्माण करना था जो न केवल भाषाई रूप से एक समान हों ताकि जनता और सरकार के मध्य संवाद सुगम हो, अपितु भौगोलिक रूप से भी सुगठित हों ताकि प्रशासनिक प्रबंधन सरल हो सके। मध्य प्रदेश का गठन इसी दृष्टि से किया गया था, जहाँ हिंदी भाषी क्षेत्रों को एकीकृत कर एक निरंतर भौगोलिक इकाई निर्मित की गई। इस संरचना ने राज्य के भीतर सांस्कृतिक एकता को प्रोत्साहित किया और एक विशाल भू-भाग को एक साझा प्रशासनिक ढांचे के अंतर्गत लाकर संतुलित क्षेत्रीय विकास हेतु एक सुदृढ़ आधार प्रदान किया।

285. (A) अविभाजित राज्य की विरासत से अलग अपनी स्वयं की पहचान विकसित करना।
वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ के गठन के पश्चात, मध्य प्रदेश के समक्ष अपनी एक नई और विशिष्ट पहचान विकसित करने की चुनौती और अवसर दोनों थे। अविभाजित राज्य की 'विशालता' और 'खनिज संपदा' वाली पहचान अब छत्तीसगढ़ के साथ संलग्न

NODIA

थी, इसलिए मध्य प्रदेश ने अपनी नई रणनीति में कृषि, पर्यटन और सेवा क्षेत्र को प्रमुखता प्रदान करना प्रारंभ किया। राज्य ने अपनी भौगोलिक स्थिति को 'भारत के हृदय' के रूप में प्रयोग करना और अपनी समृद्ध ऐतिहासिक व सांस्कृतिक विरासत को आधुनिक विकास के साथ संयोजित करना अपनी राजनीति का मुख्य निर्धारक बनाया। यह पहचान अब एक 'कृषि शक्ति' और 'सुशासन वाले राज्य' के रूप में उभर रही है, जो अपनी स्वयं की विशिष्ट प्रगति की कहानी कह रही है।

286. (B) केवल 2 और 3
मध्य प्रदेश में मंत्रिपरिषद के गठन और उत्तरदायित्व के संबंध में संवैधानिक नियम अत्यंत स्पष्ट हैं। कार्यपालिका की विधायी जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु यह अनिवार्य है कि मंत्रिपरिषद के समस्त सदस्य अनिवार्य रूप से विधानसभा के सदस्य हों। इसके साथ ही, पूरी मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति जवाबदेह होती है, जिसका अर्थ है कि वह सदन के बहुमत का विश्वास खोने पर सत्ता में नहीं रह सकती। यद्यपि, मंत्रियों के वेतन और भत्तों का निर्धारण राज्यपाल द्वारा नहीं, अपितु राज्य विधायिका द्वारा कानून निर्मित कर किया जाता है। यह वित्तीय नियंत्रण विधायी स्वायत्तता और निर्वाचित प्रतिनिधियों की सर्वोच्चता को बनाए रखने हेतु आवश्यक है।

287. (A) अध्यक्ष
मध्य प्रदेश विधानसभा में 'दलबदल विरोधी कानून' के अंतर्गत किसी सदस्य की अयोग्यता का प्रश्न उत्पन्न होने पर निर्णय लेने का सर्वोच्च और अंतिम अधिकार विधानसभा अध्यक्ष के पास होता है। यदि कोई सदस्य स्वेच्छा से अपने दल की सदस्यता त्यागता है या दल के निर्देशों के विरुद्ध मतदान करता है, तो अध्यक्ष को यह निश्चित करना होता है कि क्या संबंधित सदस्य की सदस्यता समाप्त की जानी चाहिए। यद्यपि अध्यक्ष का यह निर्णय अब न्यायिक समीक्षा के अधीन है, किंतु प्राथमिक और निर्णायक भूमिका उन्हीं की होती है। यह शक्ति अध्यक्ष को सदन में अनुशासन बनाए रखने और राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित करने हेतु एक अत्यंत प्रभावशाली विधिक उपकरण प्रदान करती है।

288. (A) P-1, Q-3, R-2, S-4
मध्य प्रदेश की राजव्यवस्था इन चार महत्वपूर्ण संवैधानिक और राजनीतिक स्तंभों पर आधारित है। सामूहिक उत्तरदायित्व का अर्थ है कि पूर्ण मंत्रिपरिषद एक इकाई के रूप में कार्य करती है और सदन के प्रति संयुक्त रूप से जवाबदेह है। विवेकाधीन शक्ति राज्यपाल को कुछ विशेष परिस्थितियों में स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार प्रदान करती है, जो संघीय संतुलन हेतु आवश्यक है। न्यायिक पुनरावलोकन उच्च न्यायालय की वह शक्ति है जिससे वह विधानमंडल द्वारा निर्मित कानूनों की संवैधानिकता की जांच करता है। अंत में, द्विध्रुवीय दलीय व्यवस्था राज्य की चुनावी राजनीति की पहचान है जहाँ दो प्रमुख दलों के मध्य प्रतिस्पर्धा होती है। ये समस्त तत्व राज्य के लोकतंत्र को व्यवस्थित और जवाबदेह निर्मित करते हैं।

289. (A) निरंकुश
लोकतंत्र में विपक्ष की सर्वाधिक महत्वपूर्ण और अनिवार्य भूमिका यह सुनिश्चित करना है कि सत्तारूढ़ सरकार कभी भी 'निरंकुश' या तानाशाह न बन सके। प्रचंड बहुमत वाली सरकारें अक्सर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर सकती हैं या अल्पसंख्यकों के हितों की उपेक्षा कर सकती हैं। विपक्ष सरकार के प्रत्येक निर्णय पर प्रश्न उठाकर, सार्वजनिक चर्चाओं को प्रोत्साहित करके और जनहित के मुद्दों पर आंदोलन करके सत्ता पर निरंतर अंकुश लगाए रखता है। एक सशक्त विपक्ष ही कार्यपालिका को सदैव यह स्मरण कराता रहता है कि वह असीमित नहीं है और उसे अपनी प्रत्येक नीति हेतु जनता और संविधान के प्रति जवाबदेह होना होगा। यही निरंतर निगरानी लोकतांत्रिक स्वतंत्रता की वास्तविक रक्षा करती है।

290. (A) उनके मतदान निर्णय को प्रभावित करने वाले कारक।
'मतदान व्यवहार' का अध्ययन केवल यह नहीं अन्वेषण करता कि कितने मत पड़े, अपितु यह उन गहरे सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारणों का विश्लेषण करता है जो मतदाता के अंतिम निर्णय को आकार प्रदान करते हैं। इसमें यह अन्वेषण किया जाता है कि जातिगत व सामुदायिक पहचान, आर्थिक मुद्दे जैसे महंगाई या रोजगार, और राजनीतिक नेतृत्व का करिश्मा किस प्रकार मतदाताओं को किसी विशेष दल की ओर आकर्षित करते हैं। मध्य प्रदेश के संदर्भ में, ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक निष्ठा और शहरी क्षेत्रों में विकास के मुद्दों का प्रभाव मतदान व्यवहार को भिन्न-भिन्न रूप में प्रभावित करता है। यह विश्लेषण निर्वाचन परिणामों को समझने और भविष्य की राजनीतिक प्रवृत्तियों का अनुमान लगाने हेतु अत्यंत आवश्यक है।

291. (A) कूटनीतिक शक्ति
मध्य प्रदेश के राज्यपाल के पास राज्य स्तर पर व्यापक विधायी, कार्यकारी और न्यायिक शक्तियां होती हैं, जैसे विधानसभा सत्र आहूत करना, मुख्यमंत्री की नियुक्ति और अपराधियों की सजा न्यून करना। यद्यपि, राज्यपाल के पास कोई 'कूटनीतिक शक्ति' नहीं होती है। कूटनीतिक शक्तियां, जिनमें अंतरराष्ट्रीय संधियाँ करना, अन्य देशों के साथ संबंध निर्मित करना और राजदूतों की नियुक्ति करना सम्मिलित है, पूर्णतः भारत के राष्ट्रपति और केंद्र सरकार के अनन्य अधिकार क्षेत्र में आती हैं। राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में राज्यपाल का कार्यक्षेत्र केवल राज्य की आंतरिक संवैधानिक व्यवस्था और केंद्र-राज्य समन्वय तक ही सीमित रहता है, अंतरराष्ट्रीय संबंधों तक नहीं।

292. (A) सलाहकार और राज्य के प्रमुख का।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल के मध्य का संबंध भारतीय संसदीय लोकतंत्र की धुरी है। राज्यपाल राज्य के संवैधानिक प्रमुख होते हैं, जिनके नाम से शासन संचालित होता है, जबकि मुख्यमंत्री वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होते हैं जो शासन का संचालन करते हैं। संविधान के अनुसार, मुख्यमंत्री का यह प्राथमिक कर्तव्य है कि वे राज्यपाल को शासन और विधायी प्रस्तावों के संबंध में निरंतर सहायता और 'परामर्श' प्रदान करें। राज्यपाल सामान्यतः इसी परामर्श के अनुसार

Click Here to Buy book on Amazon

अध्याय 10
मध्य प्रदेश की राजनीति एवं प्रशासन

1. मध्य प्रदेश के प्रशासन के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन 'सचिवालय' को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है?
(A) नीति निर्माण और नीति समीक्षा के लिए जिम्मेदार निर्वाचित प्रतिनिधियों का निकाय।
(B) नीति निर्माण और निगरानी के लिए राज्य सरकार का मुख्य प्रशासनिक कार्यालय।
(C) राज्य का न्यायिक मुख्यालय जो निचली अदालतों के कानूनी कामकाज की देखरेख करता है।
(D) सार्वजनिक सेवाओं के लिए राज्य स्तरीय परीक्षाएं आयोजित करने हेतु गठित एक विशेष एजेंसी।

2. मध्य प्रदेश में स्थानीय स्वशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन I: ग्रामीण और शहरी दोनों स्थानीय स्वशासन का प्राथमिक उद्देश्य सत्ता का विकेंद्रीकरण करना और जमीनी लोकतंत्र को बढ़ावा देना है।
कथन II: राज्य में स्थानीय स्वशासन निकायों के प्रभावी कामकाज के लिए वित्तीय स्वायत्तता एक महत्वपूर्ण कारक है।
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
(D) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।

3. मध्य प्रदेश में राज्य प्रशासनिक तंत्र का प्रमुख किस अधिकारी को माना जाता है?
(A) राज्यपाल
(B) मुख्यमंत्री
(C) मुख्य सचिव
(D) आयुक्त

4. निम्नलिखित अभिकथन (A) और कारण (R) पर विचार कीजिए:
अभिकथन (A): मध्य प्रदेश में जिला कलेक्टर जिला प्रशासन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
कारण (R): कलेक्टर जिले में राजस्व संग्रहण, कानून और व्यवस्था बनाए रखने और विकास गतिविधियों के समन्वय के लिए मुख्य अधिकारी होता है।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

5. मध्य प्रदेश में स्थानीय स्वशासन में नौकरशाही की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
(A) नौकरशाही निर्वाचित प्रतिनिधियों को तकनीकी और प्रशासनिक सहायता प्रदान करती है।
(B) नौकरशाही की उपस्थिति कभी-कभी अधिकारियों और निर्वाचित सदस्यों के बीच संघर्ष का कारण बन सकती है।
(C) स्थानीय निकायों में नौकरशाही पूरी तरह से राज्य प्रशासनिक सेवाओं से स्वतंत्र होती है।
(D) राज्य सरकार के अधिकारियों को अक्सर शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों में प्रमुख पदों पर सेवा देने के लिए प्रतिनियुक्त किया जाता है।

NODIA

6. मध्य प्रदेश के एक प्रमुख शहर में एक नवनिर्वाचित नगर निगम कचरा प्रबंधन और डिजिटल सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए 'स्मार्ट सिटी' पहल शुरू करने का निर्णय लेता है। यह कार्रवाई किसका प्रत्यक्ष उदाहरण है?
(A) स्थानीय मामलों में राज्य सचिवालय का हस्तक्षेप।
(B) शहरी स्थानीय स्तर पर विकास की राजनीति।
(C) जनजातीय वर्गों का सशक्तिकरण।
(D) नक्सली समस्या का समाधान।

7. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:
सूची I: (प्रशासनिक पद)
P. मुख्य सचिव
Q. कलेक्टर
R. आयुक्त (शहरी प्रशासन)
S. सचिव (गृह विभाग)
सूची II: (प्राथमिक कार्यक्षेत्र)
1. जिला स्तरीय प्रशासन
2. कानून और व्यवस्था पर राज्य स्तरीय नीति
3. राज्य नौकरशाही का शीर्ष पद
4. नगर निगमों की देखरेख
(A) P-3, Q-1, R-4, S-2
(B) P-1, Q-3, R-2, S-4
(C) P-3, Q-2, R-4, S-1
(D) P-4, Q-1, R-3, S-2

8. मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के सशक्तिकरण की रणनीति में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त पहला कदम होगा?
(A) लक्षित शैक्षिक और आर्थिक उत्थान कार्यक्रमों को लागू करना।

300. (A) विधानसभा में बहुमत वाले दल या गठबंधन का।
मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री राज्य की लोकतांत्रिक व्यवस्था में सर्वाधिक शक्तिशाली पद है क्योंकि वह प्रत्यक्ष रूप से 'जनता के विश्वास' का प्रतिनिधित्व करता है। मुख्यमंत्री वह व्यक्ति होता है जिसे विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों के 'बहुमत' का समर्थन प्राप्त होता है। राज्यपाल उसी नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करने हेतु आबद्ध हैं जो या तो अपने अकेले दल के स्पष्ट बहुमत का नेतृत्व करता हो या फिर निर्वाचन पूर्व अथवा निर्वाचन पश्चात निर्मित 'गठबंधन' का निर्विवाद नेता हो। मुख्यमंत्री की यह स्थिति उन्हें न केवल सरकार का प्रमुख बनाती है, अपितु उन्हें राज्य की जनता की आकांक्षाओं को विधायी और कार्यकारी रूप प्रदान करने का वास्तविक अधिकार और उत्तरदायित्व भी प्रदान करती है।

www.nodia.in

Downloaded from www.pdf.tube

कार्य करने हेतु आबद्ध हैं। यह एक सहयोगपूर्ण संबंध है जहाँ राज्यपाल एक अनुभवी अभिभावक और मार्गदर्शक की भूमिका निर्वहन करते हैं, जबकि मुख्यमंत्री निर्वाचित नेतृत्व का प्रतिनिधित्व करते हुए शासन को दिशा प्रदान करते हैं।

293. (A) संसद
सामान्य परिस्थितियों में मध्य प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल पांच वर्ष का होता है, किंतु यदि देश में 'राष्ट्रीय आपातकाल' क्रियाशील हो, तो इसके कार्यकाल को विस्तारित किया जा सकता है। यह शक्ति न तो राज्यपाल के पास है और न ही स्वयं राज्य विधायिका के पास; केवल भारत की 'संसद' ही कानून निर्मित कर विधानसभा के कार्यकाल को एक बार में एक वर्ष हेतु विस्तारित कर सकती है। आपातकाल समाप्त होने के पश्चात यह विस्तार छह माह की अवधि से अधिक नहीं हो सकता। यह संवैधानिक प्रावधान सुनिश्चित करता है कि संकट के समय देश की एकता और स्थिरता बनाए रखने हेतु विधायी निरंतरता बनी रहे, जबकि अंतिम निर्णय लेने का अधिकार संसद के पास सुरक्षित रहता है।

294. (A) विनियामक शक्तियां।
मध्य प्रदेश विधानसभा के भीतर मर्यादा, अनुशासन और सुचारु संचालन सुनिश्चित करने हेतु अध्यक्ष जो कदम उठाते हैं, वे उनकी 'विनियामक शक्तियों' का भाग हैं। इन शक्तियों के अंतर्गत अध्यक्ष यह निश्चित करते हैं कि कौन सा सदस्य कब बोलेगा, कितनी अवधि तक बोलेगा और क्या उनके शब्द सदन की गरिमा के अनुरूप हैं। वे असंसदीय भाषा को अभिलेख से निष्कासित कर सकते हैं और अभद्र व्यवहार करने वाले सदस्यों को सदन से निष्कासित भी कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करना कि विधायी चर्चा नियमों के अनुसार और बिना किसी बाधा के हो, अध्यक्ष का प्राथमिक दायित्व है। उनकी ये शक्तियां सदन की स्वायत्तता बनाए रखने हेतु अनिवार्य हैं।

295. (A) ऐसे अन्य न्यायाधीश जिन्हें राष्ट्रपति समय-समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझें।
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का संगठन एक गतिशील संरचना है जो राज्य की न्यायिक आवश्यकताओं और प्रकरणों के भार के आधार पर निर्धारित होती है। संविधान के अनुसार, प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और इसके अतिरिक्त उतने 'अन्य न्यायाधीश' होते हैं जिन्हें भारत के राष्ट्रपति समय-समय पर नियुक्त करना आवश्यक समझें। न्यायाधीशों की कोई एक निश्चित संख्या संविधान में निर्धारित नहीं है; यह पूर्णतः कार्यभार और न्यायिक दक्षता को दृष्टिगत रखते हुए राष्ट्रपति के विवेकाधीन निर्णय पर निर्भर करता है। यह लचीलापन सुनिश्चित करता है कि न्यायपालिका बढ़ते हुए प्रकरणों के भार को वहन करने हेतु सक्षम बनी रहे और न्यायाधीशों की पर्याप्त संख्या के माध्यम से जनता को त्वरित न्याय प्राप्त हो सके।

296. (A) कार्यकर्ता-आधारित और जन-आधारित संगठन।
मध्य प्रदेश की राजनीति में प्रभावी रहने वाले प्रमुख दल, जैसे भाजपा और कांग्रेस, मुख्य रूप से अपने विस्तृत 'कार्यकर्ता-आधारित' और 'जन-आधारित' ढांचे हेतु जाने जाते हैं। इन दलों की जड़ें राज्य के प्रत्येक ग्राम और वार्ड तक विस्तृत हैं, जहाँ उनके समर्पित कार्यकर्ता पार्टी की विचारधारा और नीतियों को जनता तक पहुँचाते हैं। यह संगठनात्मक सुदृढ़ता ही उन्हें निर्वाचनों के दौरान मतदाताओं को गोलबंद करने और विशाल स्तर पर जनसमर्थन अर्जित करने में सक्षम बनाती है। वे केवल निर्वाचन के समय सक्रिय नहीं होते, अपितु निरंतर विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रमों के माध्यम से जनता से जुड़े रहते हैं। यह व्यापक जन-आधार ही राज्य में इन राष्ट्रीय दलों के राजनीतिक प्रभुत्व का मुख्य कारण है।

297. (A) राष्ट्रीय एकीकरण और राज्य निर्माण।
1956 में मध्य प्रदेश का गठन केवल एक प्रशासनिक परिवर्तन नहीं था, अपितु यह स्वतंत्र भारत के 'राष्ट्रीय एकीकरण' की दिशा में उठाया गया एक अत्यंत साहसिक और ऐतिहासिक कदम था। इस प्रक्रिया ने विभिन्न लघु रियासतों और भाषाई क्षेत्रों को एकत्रित कर एक विशाल और शक्तिशाली राज्य की आधारशिला रखी। इसने प्रशासनिक विखंडन को समाप्त कर एक एकीकृत शासन प्रणाली और साझा सांस्कृतिक पहचान को जन्म दिया। 'राज्य निर्माण' की यह प्रक्रिया भाषाई पुनर्गठन के साथ-साथ देश की आंतरिक सुरक्षा और आर्थिक सुदृढ़ता हेतु भी आवश्यक थी। इस एकीकरण ने मध्य भारत को एक नई राजनीतिक शक्ति और संगठित पहचान प्रदान की, जो भारत के संघीय ढांचे को सुदृढ़ करने में सहायक सिद्ध हुई।

298. (C) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश का विभाजन और छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण भारत के राजनीतिक इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। यह विभाजन 'मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम' के माध्यम से संपन्न हुआ था, जिसका उद्देश्य प्रशासनिक सुगमता और क्षेत्रीय विकास को गति प्रदान करना था। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों के निर्माण या विभाजन हेतु किसी 'जनमत संग्रह' की आवश्यकता नहीं होती है। यह प्रक्रिया पूर्णतः विधायी और संवैधानिक है, जहाँ संसद संबंधित राज्य विधानसभा का दृष्टिकोण जानने के पश्चात कानून पारित करती है। अतः छत्तीसगढ़ का निर्माण क्षेत्रीय आकांक्षाओं और विधायी निर्णय का परिणाम था, न कि किसी सार्वजनिक मतदान या जनमत संग्रह का।

299. (A) विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकते हैं।
मध्य प्रदेश के राज्यपाल के पास राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों के संबंध में महत्वपूर्ण विवेकाधीन शक्तियां हैं। यदि राज्यपाल को प्रतीत होता है कि कोई विधेयक भारत के संविधान के प्रावधानों के प्रतिकूल है, या विशेष रूप से 'राज्य के नीति निर्देशक तत्वों' की भावना का उल्लंघन करता है, तो वे अनुच्छेद 201 के तहत उस विधेयक को अपनी सहमति प्रदान करने के स्थान पर 'राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित' कर सकते हैं। यह शक्ति राज्यपाल को राज्य में संवैधानिक मर्यादा बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने का अधिकार प्रदान करती है कि राज्य के कानून राष्ट्रीय नीति और संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप हों। एक बार आरक्षित होने के पश्चात, उस विधेयक पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार राष्ट्रपति के पास चला जाता है।

NODIA

(B) आर्थिक उपायों के बिना केवल राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर ध्यान देना।
(C) सभी आरक्षण नीतियों को तत्काल समाप्त करना।
(D) सभी विकास निधियों को गैर-सरकारी संगठनों को हस्तांतरित करना।

9. मध्य प्रदेश की राजनीति में महिलाओं के योगदान में निम्नलिखित में से किसे छोड़कर सभी शामिल हैं?
(A) राज्य मंत्रिमंडल में प्रमुख मंत्री पदों को संभालना।
(B) आरक्षण नीतियों के कारण स्थानीय स्वशासन निकायों में सक्रिय रूप से भाग लेना।
(C) सभी विधायी कार्यवाही और पार्टी नेतृत्व की भूमिकाओं पर विशेष रूप से हावी होना।
(D) महिलाओं के अधिकारों के लिए सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों का नेतृत्व करना।

10. मध्य प्रदेश में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. ग्रामीण स्थानीय निकायों के पास कुछ कर और शुल्क लगाने और वसूलने की शक्ति है।
2. वे केंद्र और राज्य सरकार की विकास योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं।
3. उनके पास उच्च न्यायालय के समकक्ष न्यायिक शक्तियां हैं।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1
(D) 1, 2 और 3

11. मध्य प्रदेश में शहरी स्थानीय स्वशासन निकायों के लिए अपर्याप्त वित्तीय स्वायत्तता का संभावित प्रभाव क्या हो सकता है?
(A) दक्षता में वृद्धि और परियोजनाओं का तेजी से पूरा होना।
(B) नवीन, आत्मनिर्भर राजस्व मॉडल के निर्माण में वृद्धि।
(C) नगरपालिका कार्यों पर नौकरशाही नियंत्रण में कमी।
(D) राज्य सरकार के अनुदानों पर अधिक निर्भरता, जिससे संभावित रूप से स्थानीय प्राथमिकताओं से समझौता हो सकता है।

12. मध्य प्रदेश प्रशासन के संबंध में सही युग्म की पहचान कीजिए।
(A) मुख्य सचिव - राज्य विधानमंडल के प्रमुख
(B) आयुक्त - एक संभाग (कई जिलों) के प्रमुख
(C) कलेक्टर - नगर निगम के प्रमुख
(D) सचिव - राज्य न्यायपालिका के प्रमुख

13. मध्य प्रदेश में निम्नलिखित प्रशासनिक इकाइयों को उनके विशिष्ट पदानुक्रमित अधिकार के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए।
1. सचिवालय
2. जिला प्रशासन
3. आयुक्त कार्यालय (संभाग)
4. तहसील कार्यालय

सही क्रम चुनिए:
(A) 1, 3, 2, 4
(B) 1, 2, 3, 4
(C) 3, 1, 4, 2
(D) 2, 3, 1, 4

14. मध्य प्रदेश के एक आदिवासी जिले की जिला पंचायत को जनजातीय कल्याण के लिए केंद्र सरकार की योजना के तहत एक बड़ा अनुदान प्राप्त होता है। हालांकि, निर्वाचित अध्यक्ष और मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जो एक आईएएस अधिकारी हैं, के बीच प्राथमिकता वाले गांवों को लेकर असहमति है। यह स्थिति किसके महत्व और संघर्ष की संभावना को उजागर करती है?
(A) जिला मामलों में मुख्य सचिव की अप्रासंगिकता।
(B) शहरी स्थानीय निकायों की शक्तियां।
(C) गैर-आदिवासी क्षेत्रों में विकास की राजनीति।
(D) स्थानीय स्वशासन में वित्त और नौकरशाही की भूमिका।

15. मध्य प्रदेश में वंचित वर्गों से संबंधित राजनीतिक परिदृश्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
(A) सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के मुद्दे वंचित वर्गों के लिए राजनीतिक विमर्श के केंद्र में हैं।
(B) मध्य प्रदेश में वंचित वर्गों को किसी सामाजिक या आर्थिक चुनौती का सामना नहीं करना पड़ता है।
(C) राजनीतिक सशक्तिकरण ने वंचना के सभी मुद्दों को पूरी तरह से हल कर दिया है।
(D) वंचित वर्गों के उत्थान के लिए सरकार की कोई नीति नहीं है।

16. निम्नलिखित अभिकथन (A) और कारण (R) पर विचार कीजिए:
अभिकथन (A): मध्य प्रदेश में स्थानीय स्वशासन निकायों के प्रभावी कामकाज के लिए उन्हें वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करना आवश्यक है।
कारण (R): वित्तीय स्वतंत्रता के बिना, स्थानीय निकाय राज्य सरकार पर अत्यधिक निर्भर रहते हैं, जो स्थानीय आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से संबोधित करने की उनकी क्षमता में बाधा डाल सकता है।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

17. मध्य प्रदेश की राजनीति के संदर्भ में 'महिलाओं का सशक्तिकरण' शब्द मुख्य रूप से क्या दर्शाता है?
(A) नीतिगत भूमिकाओं से बाहर रखते हुए महिलाओं की भागीदारी को केवल सामाजिक मुद्दों तक सीमित रखना।

Click Here to Buy book on Amazon

(A) 2, 1, 3, 4
(B) 1, 2, 3, 4
(C) 3, 4, 1, 2
(D) 2, 4, 1, 3

37. निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आमतौर पर मध्य प्रदेश सचिवालय में एक सचिव से जुड़ा होता है?
(A) एक जिले के मुख्य कार्यकारी के रूप में कार्य करना।
(B) ग्राम पंचायत की बैठक की अध्यक्षता करना।
(C) एक विशिष्ट सरकारी विभाग के प्रशासन का नेतृत्व करना।
(D) एक मंत्रालय के राजनीतिक प्रमुख के रूप में कार्य करना।

38. मध्य प्रदेश में एक जनपद पंचायत का सफल संचालन किसके बीच सहकारी संबंध पर बहुत अधिक निर्भर करता है?
(A) जनपद पंचायत और संयुक्त राष्ट्र।
(B) निर्वाचित प्रतिनिधि और प्रतिनियुक्त सरकारी अधिकारी।
(C) कलेक्टर और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश।
(D) महापौर और नगर निगम आयुक्त।

39. मध्य प्रदेश में जिला प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. कलेक्टर जिले का एकमात्र प्राधिकारी है और वहां कोई अन्य विभाग कार्य नहीं करता है।
2. पुलिस अधीक्षक पुलिस प्रशासन के लिए जिम्मेदार होता है और कानून-व्यवस्था पर जिला मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट करता है।
3. सभी विकास योजनाएं विशेष रूप से जिला प्रशासन द्वारा ही परिकल्पित और वित्तपोषित की जाती हैं।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) केवल 2
(B) केवल 1 और 3
(C) केवल 3
(D) 1, 2 और 3

40. मध्य प्रदेश सरकार द्वारा महिला और बाल विकास के लिए बजटीय आवंटन में वृद्धि को किसके प्रत्यक्ष योगदान के रूप में देखा जा सकता है?
(A) महिलाओं का सशक्तिकरण और राज्य की विकास राजनीति का हिस्सा।
(B) शहरी स्थानीय निकायों की संगठनात्मक संरचना।
(C) पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा विवादों का समाधान।
(D) मुख्य सचिव की शक्तियां।

41. मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
(A) मुख्य सचिव राज्य में सिविल सेवाओं का प्रमुख होता है।
(B) मुख्य सचिव राज्य मंत्रिमंडल के सचिव के रूप में कार्य करता है।
(C) मुख्य सचिव का पद पांच वर्ष की निश्चित अवधि के लिए एक कार्यकाल पद है।
(D) मुख्य सचिव का चयन मुख्यमंत्री द्वारा वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों में से किया जाता है।

42. मध्य प्रदेश के राजनीतिक संदर्भ में 'वंचित वर्ग' शब्द आमतौर पर उन समूहों को संदर्भित करता है जो ऐतिहासिक रूप से किसके आधार पर हाशिए पर रहे हैं?
(A) जाति, वर्ग और सामाजिक स्थिति।
(B) राजनीतिक संबद्धता।
(C) आधुनिक अर्थव्यवस्था में पेशे का चुनाव।
(D) शहरी केंद्रों के भीतर भौगोलिक स्थिति।

43. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:
सूची I: (निकाय)
P. राज्य सचिवालय
Q. जिला पंचायत
R. नगर निगम
S. ग्राम सभा
सूची II: (प्राथमिक कार्य)
1. ग्राम पंचायत के वार्षिक खातों की समीक्षा करना
2. एक बड़े शहर में नागरिक सुविधाएं प्रदान करना
3. एक जिले में ग्रामीण विकास की समग्र निगरानी
4. पूरे राज्य के लिए नीति निर्माण
(A) P-4, Q-3, R-2, S-1
(B) P-1, Q-2, R-3, S-4
(C) P-4, Q-2, R-3, S-1
(D) P-3, Q-4, R-1, S-2

44. विकास की राजनीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन I: मध्य प्रदेश में विकास की राजनीति राजनीतिक विचारों से पूरी तरह मुक्त है और विशुद्ध रूप से तकनीकी आवश्यकता आकलन पर आधारित है।
कथन II: विकास परियोजनाओं का आवंटन अक्सर सत्तारूढ़ दल की प्राथमिकताओं और राजनीतिक लक्ष्यों को दर्शाता है।
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
(D) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।

45. जिले में एक समन्वयक के रूप में कलेक्टर की भूमिका में क्या शामिल है?
(A) जिले में तैनात सैन्य बलों की प्रत्यक्ष कमान संभालना।
(B) मध्य प्रदेश राज्य के लिए विदेश नीति तैयार करना।
(C) विभिन्न सरकारी विभागों के बीच सामंजस्य और कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।
(D) जिला अदालत में न्यायाधीशों की नियुक्ति करना।

46. निम्नलिखित अभिकथन (A) और कारण (R) पर विचार कीजिए:

NODIA

(C) विशेष रूप से शहरी स्थानीय स्वशासन संरचना के भीतर।
(D) कलेक्टर के ऊपर और वह एक संभाग का प्रभारी होता है।

28. मध्य प्रदेश में राजमार्गों और सिंचाई नहरों जैसी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर बढ़ा हुआ राजनीतिक ध्यान किसकी अभिव्यक्ति है?
(A) नक्सली समस्या
(B) विकास की राजनीति
(C) सचिवालय की संगठनात्मक संरचना
(D) स्थानीय स्वशासन की स्वायत्तता

29. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:
सूची I: (पद)
P. सरपंच
Q. महापौर
R. मुख्य सचिव
S. जिला मजिस्ट्रेट
सूची II: (संबद्ध निकाय/अवधारणा)
1. नगर निगम
2. ग्राम पंचायत
3. कलेक्टर
4. राज्य सचिवालय
(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-2, Q-1, R-4, S-3
(C) P-2, Q-3, R-4, S-1
(D) P-4, Q-1, R-2, S-3

30. निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश में जिला कलेक्टर की प्राथमिक भूमिका नहीं है?
(A) जिले के मुख्य राजस्व अधिकारी के रूप में कार्य करना।
(B) जिला मजिस्ट्रेट के रूप में कानून और व्यवस्था बनाए रखना।
(C) जिले में विभिन्न सरकारी विभागों की गतिविधियों का समन्वय करना।
(D) राज्य विधानसभा के सत्रों की अध्यक्षता करना।

31. मध्य प्रदेश की प्रशासनिक संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन I: मध्य प्रदेश में सचिवालय एक विशुद्ध रूप से राजनीतिक निकाय है जिसमें निर्वाचित विधायक शामिल होते हैं।
कथन II: मुख्य सचिव सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख होता है।
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
(D) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।

32. मध्य प्रदेश में स्थानीय स्वशासन के लिए 'स्वायत्तता' की अवधारणा का सर्वोत्तम तात्पर्य क्या है?
(A) राज्य सरकार और उसकी विधायी निगरानी से पूर्ण प्रशासनिक अलगाव।
(B) राज्य सरकार के अनुचित हस्तक्षेप के बिना एक परिभाषित क्षेत्र के भीतर कार्यात्मक स्वतंत्रता।
(C) एक स्वतंत्र राज्य स्तरीय पुलिस बल बनाने और प्रबंधित करने की विशिष्ट कानूनी शक्ति।
(D) सभी मौजूदा राज्य और केंद्रीय विधायी ढांचे की अवहेलना करने का संवैधानिक अधिकार।

33. निम्नलिखित अभिकथन (A) और कारण (R) पर विचार कीजिए:
अभिकथन (A): आदिवासी आबादी की सामाजिक-आर्थिक शिकायतों को दूर करना मध्य प्रदेश में नक्सली समस्या से निपटने का एक प्रमुख घटक है।
कारण (R): नक्सली विचारधारा अक्सर गरीबी, शोषण और शासन की कथित कमी वाले क्षेत्रों में पकड़ बनाती है।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

34. निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश में 'विकास की राजनीति' का एक प्रमुख पहलू है?
(A) राजनीतिक समर्थन हासिल करने के लिए विकास परियोजनाओं हेतु कुछ क्षेत्रों या सामाजिक समूहों को प्राथमिकता देना।
(B) विशेष रूप से अंतरराष्ट्रीय कूटनीति पर ध्यान केंद्रित करना।
(C) विधायी प्रक्रिया के नियमों में संशोधन करना।
(D) मुख्य सचिव की नियुक्ति की प्रक्रिया।

35. मध्य प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य में पिछड़े वर्गों के सशक्तिकरण में अक्सर क्या शामिल होता है?
(A) विधायी आदेश द्वारा जाति व्यवस्था का उन्मूलन।
(B) राजनीतिक प्रक्रिया में उनकी भागीदारी को सीमित करना।
(C) सरकारी नौकरियों और शिक्षा में सकारात्मक कार्रवाई और आरक्षण की नीतियां।
(D) अन्य राज्यों में प्रवास को प्रोत्साहित करना।

NODIA

36. मध्य प्रदेश में एक नगर निगम के भीतर एक सामान्य विकास परियोजना अनुमोदन प्रक्रिया की घटनाओं को क्रमबद्ध कीजिए।
1. परिषद द्वारा बजट की स्वीकृति।
2. किसी समिति या विभाग द्वारा परियोजना का प्रस्ताव।
3. निविदा और अनुबंध प्रदान करना।
4. परियोजना का क्रियान्वयन और निगरानी।
सही क्रम चुनिए:

(B) संसाधनों, निर्णय लेने की प्रक्रिया और राजनीतिक भागीदारी तक महिलाओं की पहुंच बढ़ाना।
(C) सभी राज्य निकायों में पुरुषों से महिलाओं को राजनीतिक शक्ति का पूर्ण हस्तांतरण।
(D) केवल शहरी महिला आबादी के आर्थिक विकास पर केंद्रित नीति।

18. "मध्य प्रदेश में विकास की राजनीति" मुख्य रूप से किस प्रमुख गतिविधि के इर्द-गिर्द घूमती है?
(A) बुनियादी ढांचे, सामाजिक कल्याण और आर्थिक विकास के लिए राज्य संसाधनों के आवंटन की प्रक्रिया।
(B) राज्य सरकार द्वारा अंतरराष्ट्रीय संबंधों का संचालन।
(C) उच्च न्यायालय में न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति।
(D) राज्य सचिवालय का दैनिक प्रशासन।

19. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:
सूची I: (अवधारणा)
P. नक्सली समस्या
Q. आदिवासियों का सशक्तिकरण
R. महिलाओं का योगदान
S. विकास की राजनीति
सूची II: (मध्य प्रदेश की राजनीति में प्रासंगिकता)
1. पंचायतों में आरक्षण
2. औद्योगिक निवेश और बुनियादी ढांचा
3. विशिष्ट जिलों में सुरक्षा और सामाजिक-आर्थिक मुद्दा
4. पेसा अधिनियम के तहत विशेष प्रावधान
(A) P-3, Q-4, R-1, S-2
(B) P-1, Q-2, R-3, S-4
(C) P-3, Q-1, R-4, S-2
(D) P-4, Q-3, R-2, S-1

20. मध्य प्रदेश में जिला कलेक्टर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन I: कलेक्टर की नियुक्ति राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है।
कथन II: कलेक्टर जिला मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य करता है और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है।
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
(D) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।

21. मध्य प्रदेश में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की त्रि-स्तरीय संरचना के शीर्ष पर कौन सा निकाय है?
(A) ग्राम सभा
(B) ग्राम पंचायत
(C) जिला पंचायत
(D) जनपद पंचायत

22. निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है?
(A) सचिवालय - राज्य स्तरीय नीति निर्धारण
(B) सरपंच - जिला पंचायत का प्रमुख
(C) कलेक्टर - जिला स्तरीय समन्वय
(D) महापौर - नगर निगम का प्रमुख

23. निम्नलिखित अभिकथन (A) और कारण (R) पर विचार कीजिए:
अभिकथन (A): मध्य प्रदेश में मुख्य सचिव को अक्सर राज्य प्रशासन की 'धुरी' कहा जाता है।
कारण (R): मुख्य सचिव मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के मुख्य सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं और अंतर-विभागीय समन्वय सुनिश्चित करते हैं।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

24. मध्य प्रदेश में नक्सली समस्या से जुड़ा एक प्रमुख मुद्दा अक्सर किससे संबंधित होता है?
(A) सुदूर आदिवासी और वन क्षेत्रों में अलगाव और विकास की कमी।
(B) शहरी स्थानीय स्वशासन का विस्तार।
(C) प्रमुख औद्योगिक शहरों में विकास की राजनीति।
(D) राज्य सचिवालय की वित्तीय स्वायत्तता।

25. 74वां संविधान संशोधन अधिनियम मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किसके संगठन और शक्तियों से संबंधित है?
(A) ग्रामीण स्थानीय स्वशासन
(B) राज्य सचिवालय
(C) शहरी स्थानीय स्वशासन
(D) कलेक्टर की भूमिका

26. मध्य प्रदेश में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. 73वें और 74वें संशोधनों ने स्थानीय निकायों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में उल्लेखनीय वृद्धि की है।
2. महिलाओं की भागीदारी केवल मतदान तक सीमित है और राजनीतिक पद धारण करने तक नहीं है।
3. राज्य के विकास में महिला राजनीतिज्ञों का योगदान नगण्य रहा है।
उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) केवल 1
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3

27. मध्य प्रदेश के प्रशासनिक पदानुक्रम में 'आयुक्त' का पद कहाँ स्थित है?
(A) कलेक्टर के नीचे लेकिन तहसीलदार के ऊपर।
(B) मुख्य सचिव के समानांतर।

Downloaded from www.pdf.tube

अभिकथन (A): 73वां संविधान संशोधन अधिनियम मध्य प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के लिए एक मील का पत्थर था।
कारण (R): इसने ग्रामीण स्थानीय स्वशासन निकायों में महिलाओं के लिए कम से कम एक-तिहाई सीटों और अध्यक्ष पदों के आरक्षण को अनिवार्य बना दिया।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

47. मध्य प्रदेश में शहरी स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में, एक 'नगर पंचायत' आम तौर पर किसका प्रशासन करती है?
(A) एक संक्रमणकालीन क्षेत्र, जो ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में विकसित हो रहा है।
(B) एक बड़ा महानगरीय शहर।
(C) एक ही प्रशासन के तहत गांवों का एक समूह।
(D) एक पूरा जिला।

48. मध्य प्रदेश के एक गांव की एक महिला सरपंच लड़कियों के लिए एक नया स्कूल बनाने के लिए समुदाय को सफलतापूर्वक लामबंद करती है। यह किसका प्रत्यक्ष उदाहरण है?
(A) राज्य नौकरशाही की विफलता।
(B) स्थानीय राजनीति और विकास में महिलाओं का योगदान।
(C) मुख्य सचिव की प्राथमिक भूमिका।
(D) शहरी स्थानीय स्वशासन की शक्तियां।

49. निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश में शहरी स्थानीय स्वशासन के लिए वित्त का स्रोत नहीं है?
(A) संपत्ति कर
(B) अंतरराष्ट्रीय व्यापार टैरिफ से राजस्व
(C) राज्य सरकार से अनुदान
(D) जल आपूर्ति और अन्य सेवाओं के लिए शुल्क

50. यदि मध्य प्रदेश सचिवालय के भीतर दो विभागों के बीच किसी नीति के क्रियान्वयन को लेकर विवाद उत्पन्न होता है, तो संघर्ष को सुलझाने और समन्वय सुनिश्चित करने के लिए सबसे उपयुक्त प्राधिकारी कौन है?
(A) मुख्य सचिव
(B) भोपाल के जिला कलेक्टर
(C) भोपाल के महापौर
(D) उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश

51. मध्य प्रदेश में नक्सली समस्या के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह विशुद्ध रूप से कानून और व्यवस्था का मुद्दा है जिसका कोई सामाजिक-आर्थिक आयाम नहीं है।
2. राज्य सरकार अक्सर सुरक्षा कार्रवाई और विकास पहल की दो-तरफा रणनीति अपनाती है।
3. यह समस्या राज्य के सभी जिलों में समान रूप से फैली हुई है।
उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) केवल 2
(B) केवल 1 और 3
(C) केवल 1
(D) 1, 2 और 3

52. मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत की स्थानीय बाजारों और स्वच्छता का प्रबंधन करने की शक्ति किसके अंतर्गत आती है?
(A) न्यायिक कार्य
(B) अंतरराष्ट्रीय संबंधों में भूमिका
(C) राज्य के संविधान में संशोधन करने का अधिकार
(D) अनिवार्य और विवेकाधीन कार्य

53. मध्य प्रदेश में प्रशासनिक संरचना के संबंध में सही कथन की पहचान कीजिए।
(A) आयुक्त प्रशासनिक रूप से जिला कलेक्टर के अधीनस्थ होता है।
(B) मुख्य सचिव राज्य सरकार का राजनीतिक प्रमुख होता है।
(C) सचिवालय राज्य प्रशासन और नीति निर्माण का तंत्रिका केंद्र है।
(D) जिला प्रशासन राज्य सरकार से पूरी तरह स्वतंत्र है।

54. मध्य प्रदेश में निम्नलिखित प्रशासनिक पदों को राजस्व मामले के लिए विशिष्ट आदेश श्रृंखला में उच्चतम से निम्नतम की ओर व्यवस्थित करें।
1. कलेक्टर
2. सचिव (राजस्व विभाग)
3. तहसीलदार
4. आयुक्त
सही अनुक्रम चुनें:
(A) 2, 4, 1, 3
(B) 4, 2, 1, 3
(C) 2, 1, 4, 3
(D) 1, 3, 4, 2

55. मध्य प्रदेश सरकार द्वारा निवेश आकर्षित करने और रोजगार सृजन के उद्देश्य से एक नई औद्योगिक नीति की घोषणा किसका स्पष्ट उदाहरण है?
(A) उच्च न्यायालय का एक न्यायिक निर्णय।
(B) ग्राम पंचायत का आंतरिक कामकाज।
(C) जिला कलेक्टर का एक नियमित कार्य।
(D) विकास की राजनीति।

56. निम्नलिखित अभिकथन (A) और कारण (R) पर विचार कीजिए:
अभिकथन (A): मध्य प्रदेश में स्थानीय स्वशासन के कामकाज में नौकरशाही एक महत्वपूर्ण, लेकिन कभी-कभी विवादास्पद भूमिका निभाती है।

NODIA

2. कानून का शासन स्थापित करने के लिए सुरक्षा बलों की तैनाती।
3. सामाजिक-आर्थिक विकास परियोजनाओं का क्रियान्वयन।
4. कैडरों के आत्मसमर्पण और पुनर्वास को प्रोत्साहित करना।

सही तार्किक क्रम चुनें:
(A) 1, 2, 3, 4
(B) 3, 4, 1, 2
(C) 1, 3, 2, 4
(D) 4, 3, 2, 1

76. मध्य प्रदेश सचिवालय में एक सरकारी विभाग का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है?
(A) मंत्री
(B) सचिव
(C) मुख्यमंत्री
(D) कलेक्टर

77. मध्य प्रदेश में स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में 'नौकरशाही' शब्द का तात्पर्य है:
(A) निर्वाचित प्रतिनिधियों का निकाय जैसे सरपंच और महापौर।
(B) राज्य स्तर पर शासन करने वाला एक राजनीतिक दल।
(C) गैर-निर्वाचित, स्थायी और पेशेवर सरकारी अधिकारी जो नीतियों को क्रियान्वित करते हैं।
(D) सामाजिक मुद्दों पर काम करने वाला एक गैर-सरकारी संगठन।

78. मध्य प्रदेश में एक महिला का जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में चुना जाना एक महत्वपूर्ण घटना है क्योंकि यह प्रदर्शित करता है:
(A) पुरुष राजनेताओं की विफलता।
(B) जिला पंचायत प्रणाली का उन्मूलन।
(C) स्थानीय चुनावों में मुख्य सचिव का सीधा हस्तक्षेप।
(D) उच्च स्तरीय स्थानीय राजनीति में महिलाओं का सफल सशक्तिकरण और योगदान।

79. मध्य प्रदेश में कलेक्टर की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. कलेक्टर जिले में सरकारी गतिविधियों का मुख्य समन्वयक होता है।
2. कलेक्टर के पास राज्य स्तरीय कानून बनाने की शक्ति होती है।
3. कलेक्टर जिला मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य करता है, जो कानून और व्यवस्था के लिए जिम्मेदार होता है।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) केवल 1 और 3
(B) केवल 2
(C) केवल 2 और 3
(D) 1, 2 और 3

80. मध्य प्रदेश में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की प्रभावशीलता अक्सर किससे बाधित होती है?
(A) अत्यधिक वित्तीय स्वायत्तता और राज्य की निगरानी की कमी।
(B) अपर्याप्त वित्त, नौकरशाही हस्तक्षेप और निर्वाचित सदस्यों की कम क्षमता।
(C) ग्राम स्तर पर किसी भी निर्वाचित प्रतिनिधि की अनुपस्थिति।
(D) जन भागीदारी या रुचि की पूरी तरह से कमी।

81. मध्य प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
(A) वंचित वर्गों का सशक्तिकरण राज्य की राजनीति में एक आवर्ती विषय है।
(B) राज्य में विकास की राजनीति पूरी तरह से अस्तित्वहीन है।
(C) राज्य को अपने कुछ जिलों में नक्सली समस्या से संबंधित चुनौतियों का सामना करना पड़ा है।
(D) महिलाओं ने राज्य के राजनीतिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

82. मध्य प्रदेश में एक नगर निगम के प्रमुख को क्या कहा जाता है?
(A) महापौर
(B) आयुक्त
(C) सरपंच
(D) कलेक्टर

83. निम्नलिखित अभिकथन (A) और कारण (R) पर विचार कीजिए:
अभिकथन (A): मध्य प्रदेश में कलेक्टर की भूमिका केवल एक राजस्व संग्रहकर्ता से विकसित होकर एक प्रमुख विकास अभिकर्ता की हो गई है।
कारण (R): केंद्र और राज्य की अनेक कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत के साथ, कलेक्टर अब जिला स्तर पर उनके क्रियान्वयन के समन्वय के लिए नोडल अधिकारी है।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

84. मध्य प्रदेश में "विकास की राजनीति" वाक्यांश का अर्थ है कि विकास गतिविधियां:
(A) हमेशा तटस्थ और वैज्ञानिक होती हैं।
(B) विशेष रूप से गैर-राजनीतिक तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा प्रबंधित की जाती हैं।
(C) राज्य के राजनीतिक विमर्श के लिए अप्रासंगिक हैं।
(D) अक्सर राजनीतिक प्रक्रियाओं, प्राथमिकताओं और श्रेय लेने की प्रतिस्पर्धा के साथ जुड़ी होती हैं।

Click Here to Buy book on Amazon

(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 2
(D) 1, 2 और 3

66. मध्य प्रदेश में राज्य सचिवालय का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?
(A) राज्य सरकार को प्रशासनिक और नीति निर्माण सहायता प्रदान करना।
(B) राज्यपाल के निवास के रूप में कार्य करना।
(C) जिला कलेक्टरों के मुख्यालय के रूप में कार्य करना।
(D) स्थानीय नगरपालिका चुनाव कराना।

67. "मध्य प्रदेश में विकास की राजनीति" में किन विषयों पर बहस और निर्णय शामिल होने की संभावना है?
(A) नए मुख्य सचिव की नियुक्ति।
(B) विधानसभा सत्र के प्रक्रियात्मक नियम।
(C) सामाजिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में निवेश बनाम नए बांध के निर्माण के लिए धन का आवंटन।
(D) तहसीलदार का आंतरिक स्थानांतरण।

68. निम्नलिखित अभिकथन (A) और कारण (R) पर विचार कीजिए:
अभिकथन (A): मध्य प्रदेश में स्थानीय स्वशासन की सफलता के लिए स्वायत्तता एक महत्वपूर्ण कारक है।
कारण (R): यदि स्थानीय निकायों में स्वायत्तता की कमी है, तो वे स्थानीय जनता की विशिष्ट आवश्यकताओं और आकांक्षाओं का प्रभावी ढंग से जवाब नहीं दे सकते हैं, जिससे विकेंद्रीकरण का उद्देश्य विफल हो जाता है।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

69. मध्य प्रदेश के एक विशिष्ट क्षेत्र में पिछड़े वर्ग के समुदाय को सशक्त बनाने के प्रयास में, सरकार एक विशेष कौशल विकास कार्यक्रम शुरू करती है और लघु व्यवसायों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यह किसका उदाहरण है?
(A) शहरी स्थानीय स्वशासन का एक नियमित कार्य।
(B) किसी असंबद्ध क्षेत्र में नक्सली समस्या का मुकाबला करने का उपाय।
(C) सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए एक राजनीतिक रणनीति।
(D) अकेले मुख्य सचिव द्वारा शक्ति का प्रयोग।

70. निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश में शहरी स्थानीय स्वशासन का निकाय नहीं है?
(A) नगर निगम
(B) जनपद पंचायत
(C) नगर पालिका परिषद
(D) नगर पंचायत

71. मध्य प्रदेश में राजस्व प्रशासन के प्रमुख और जिला मजिस्ट्रेट के रूप में कलेक्टर की दोहरी भूमिका क्या दर्शाती है?
(A) शक्तियों का एक भ्रम जिसे अलग किया जाना चाहिए।
(B) नागरिक प्रशासन पर पुलिस की श्रेष्ठता।
(C) कार्यपालिका पर न्यायपालिका का सीधा नियंत्रण।
(D) एक ऐतिहासिक विरासत जो जिला स्तर पर प्रभावी शासन के लिए अधिकार केंद्रित करती है।

72. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:
सूची I: (सरकार का स्तर)
P. राज्य सरकार
Q. जिला प्रशासन
R. नगर निगम
S. ग्राम पंचायत
सूची II: (विशिष्ट प्रमुख)
1. महापौर
2. सरपंच
3. मुख्यमंत्री
4. कलेक्टर
(A) P-3, Q-4, R-1, S-2
(B) P-1, Q-2, R-3, S-4
(C) P-3, Q-1, R-4, S-1
(D) P-4, Q-3, R-2, S-1

NODIA

73. मध्य प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य में जनजातीय वर्गों के सशक्तिकरण का उद्देश्य क्या है?
(A) उन्हें मुख्यधारा के समाज से अलग करना।
(B) उनकी अनूठी सांस्कृतिक प्रथाओं को समाप्त करना।
(C) निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना और भूमि एवं वन जैसे संसाधनों पर उनके अधिकार सुरक्षित करना।
(D) उन्हें शहरी क्षेत्रों में स्थानांतरित करना।

74. महिलाओं की भागीदारी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन I: मध्य प्रदेश की राजनीति में महिलाओं का योगदान एक हालिया घटना है जो केवल 21वीं सदी में शुरू हुई।
कथन II: मध्य प्रदेश की महिलाओं ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया है और कई दशकों से राजनीतिक पदों पर रही हैं, स्थानीय सरकार के आरक्षण से उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रूप से बढ़ी है।
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
(D) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।

75. मध्य प्रदेश में नक्सल प्रभावित क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने की सामान्य प्रक्रिया के निम्नलिखित चरणों को व्यवस्थित करें।
1. सूचना और घटनाओं के आधार पर क्षेत्र की पहचान।

बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना और उनका रखरखाव करना।

95. मध्य प्रदेश के राजनीतिक संदर्भ में वंचित वर्गों के लिए "सशक्तिकरण" की अवधारणा का मूल उद्देश्य क्या है?
(A) उनकी स्थिति को कल्याण के निष्क्रिय प्राप्तकर्ताओं से बदलकर राजनीतिक और विकास प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाना।
(B) उन्हें एक अलग और स्वतंत्र राष्ट्र प्रदान करना।
(C) राज्य के चुनावों में उनके वोट देने के अधिकार को प्रतिबंधित करना।
(D) उनकी सांस्कृतिक पहचान को मिटाते हुए, उनके पूर्ण आत्मसात को प्रोत्साहित करना।

96. मध्य प्रदेश में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के निम्नलिखित स्तरों को उनके भौगोलिक दायरे के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें।
1. जिला पंचायत
2. ग्राम पंचायत
3. जनपद पंचायत
सही क्रम चुनिए:
(A) 2, 3, 1
(B) 1, 3, 2
(C) 3, 2, 1
(D) 2, 1, 3

97. मध्य प्रदेश में विकास की राजनीति किसके ऊपर राजनीतिक विवाद का कारण बन सकती है?
(A) संयुक्त राष्ट्र में प्रक्रिया के नियम।
(B) एक नए विश्वविद्यालय या एक प्रमुख औद्योगिक संयंत्र का स्थान।
(C) विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति।
(D) सचिवालय कर्मचारियों की वर्दी का रंग।

98. मध्य प्रदेश राज्य सचिवालय का प्राथमिक कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है?
(A) नीति निर्माण, समीक्षा और पर्यवेक्षण में मंत्रियों की सहायता करना।
(B) ग्राम स्तर पर सभी योजनाओं को सीधे लागू करना।
(C) दीवानी मामलों के लिए कानून की अदालत के रूप में कार्य करना।
(D) राज्य के सभी शहरों की दैनिक स्वच्छता का प्रबंधन करना।

99. निम्नलिखित अभिकथन (A) और कारण (R) पर विचार कीजिए:
अभिकथन (A): मध्य प्रदेश में किसी जिले का कलेक्टर एक शक्तिशाली व्यक्ति होता है।
कारण (R): कलेक्टर प्रत्येक पांच वर्ष में जिले के लोगों द्वारा सीधे चुना जाता है।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

100. मध्य प्रदेश में सरपंचों और पार्षदों के रूप में महिलाओं की बड़ी संख्या में उपस्थिति मुख्य रूप से किसका परिणाम है?
(A) राजनीतिक सीटों को खाली करने के लिए पुरुषों द्वारा किया गया एक स्वैच्छिक आंदोलन।
(B) संयुक्त राष्ट्र का एक निर्देश।
(C) पुरुष उम्मीदवारों के लिए चुनाव की उच्च लागत।
(D) आरक्षण के लिए संवैधानिक और वैधानिक प्रावधान।

101. मध्य प्रदेश में ब्लॉक स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था के मध्य स्तर को क्या कहा जाता है?
(A) ग्राम सभा
(B) जिला परिषद
(C) जनपद पंचायत
(D) नगर पंचायत

102. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:
सूची I: (राजनीतिक मुद्दा)
P. आदिवासियों का सशक्तिकरण
Q. विकास की राजनीति
R. नक्सली समस्या
S. शहरी स्वशासन
सूची II: (प्राथमिक फोकस क्षेत्र)
1. बुनियादी ढांचा और निवेश
2. विशिष्ट क्षेत्रों में सुरक्षा और सामाजिक-आर्थिक पिछड़ापन
3. पेसा अधिनियम और वन अधिकार
4. शहरों में नागरिक सुविधाएं
(A) P-1, Q-3, R-2, S-4
(B) P-3, Q-1, R-2, S-4
(C) P-3, Q-2, R-1, S-4
(D) P-2, Q-1, R-4, S-3

103. स्थानीय स्वशासन में 'स्वायत्तता' के महत्व का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सा है?
(A) यह राज्य स्तरीय राजनेताओं को स्थानीय निर्णयों को अधिक प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने की अनुमति देता है।
(B) यह स्थानीय निकायों को स्थानीय परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार विकास योजनाएं बनाने में सक्षम बनाता है।
(C) यह राज्य से किसी भी वित्तीय सहायता की आवश्यकता को समाप्त कर देता है।
(D) यह नौकरशाही को पूरी तरह से गैर-जवाबदेह बनाता है।

104. जिला प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन I: कलेक्टर जिला प्रशासन का प्रमुख होता है और उसे जिला मजिस्ट्रेट के रूप में भी जाना जाता है।

Downloaded from www.pdf.tube

85. मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग का अस्तित्व क्या सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है?
(A) सचिवालय की वित्तीय स्वायत्तता।
(B) मुख्य सचिव की नियुक्ति।
(C) स्थानीय स्वशासन निकायों के चुनावों का स्वतंत्र और निष्पक्ष संचालन।
(D) वंचित वर्गों का दमन।

86. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:
सूची I: (संस्था/विषय)
P. जिला कलेक्टर
Q. ग्राम पंचायत
R. सचिवालय
S. नक्सलवाद
सूची II: (प्रासंगिक अवधारणा)
1. शीर्ष प्रशासनिक निकाय
2. जिला प्रशासन
3. ग्रामीण स्थानीय स्वशासन
4. आंतरिक सुरक्षा मुद्दा
(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-2, Q-3, R-1, S-4
(C) P-2, Q-1, R-4, S-3
(D) P-4, Q-3, R-1, S-2

87. मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्गों के सशक्तिकरण में निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रमुख चुनौती है?
(A) राज्य में पिछड़े वर्गों की पूरी तरह से अनुपस्थिति।
(B) वित्तीय संसाधनों की अधिकता जिससे कुप्रबंधन होता है।
(C) इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए भी राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी।
(D) यह सुनिश्चित करना कि आरक्षण और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचे।

88. मध्य प्रदेश में शहरी स्थानीय स्वशासन निकायों की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति किसका अधिकार है?
(A) स्थानीय आर्थिक और सामाजिक विकास की योजना बनाना और नागरिक सुविधाएं प्रदान करना।
(B) विदेश नीति तैयार करना।
(C) राज्य पुलिस को कमान देना।
(D) मुख्य सचिव की नियुक्ति करना।

89. मध्य प्रदेश के एक गांव की एक महिला सरपंच अपने गांव में कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ सफलतापूर्वक अभियान चलाती है। यह क्या दर्शाता है?
(A) सरपंच के रूप में उनकी शक्तियों का अतिक्रमण।
(B) शहरी स्थानीय सरकार की विफलता।
(C) राजनीति में महिलाओं का योगदान जो सामाजिक सुधार तक फैला हुआ है।
(D) राज्य सचिवालय की एक विशिष्ट गतिविधि।

90. मुख्य सचिव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन I: मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव डिफ़ॉल्ट रूप से पूरे देश में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले सरकारी अधिकारी होते हैं।
कथन II: मुख्य सचिव एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी होता है जिसे मुख्यमंत्री द्वारा राज्य की प्रशासनिक मशीनरी का नेतृत्व करने के लिए चुना जाता है।
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
(D) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।

91. मध्य प्रदेश के प्रशासन में आयुक्त की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा है?
(A) एक ही गांव के दैनिक मामलों का सीधे प्रबंधन करना।
(B) पूरे राज्य प्रशासन का नेतृत्व करना।
(C) एक शहरी स्थानीय निकाय के राजनीतिक प्रमुख के रूप में कार्य करना।
(D) जिलों के एक समूह (एक संभाग) में कलेक्टरों के कार्य की निगरानी और समन्वय करना।

NODIA

92. मध्य प्रदेश में "नक्सली समस्या" के इर्द-गिर्द राजनीतिक विमर्श में अक्सर किसके बीच बहस शामिल होती है?
(A) शहरी विकास बनाम ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देना।
(B) विशुद्ध रूप से सुरक्षा-आधारित दृष्टिकोण बनाम विकास-उन्मुख दृष्टिकोण।
(C) महापौर की शक्तियाँ बनाम सरपंच की शक्तियाँ।
(D) राज्य सचिवालय के भीतर पदानुक्रम।

93. मध्य प्रदेश में प्रशासन के निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए:
1. मुख्य सचिव का कार्यालय अंतर-विभागीय समन्वय सुनिश्चित करता है।
2. कलेक्टर जिले में राज्य सरकार की 'आंख, कान और हाथ' के रूप में कार्य करता है।
3. सचिवालय प्रत्येक जिला मुख्यालय में स्थित है।
उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 3
(D) 1, 2 और 3

94. मध्य प्रदेश में एक नगर पालिका परिषद की वित्तीय व्यवहार्यता उसकी किस क्षमता के लिए महत्वपूर्ण है?
(A) विदेशी व्यापार का संचालन करना।
(B) राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाना।
(C) भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति करना।
(D) सड़कों, स्ट्रीटलाइट्स और स्वच्छता जैसी स्थानीय

(A) संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्वाचन अधिकारी के रूप में कार्य करना।
(B) कई जिला स्तरीय समितियों के अध्यक्ष के रूप में सेवा करना।
(C) सार्वजनिक वितरण प्रणाली की निगरानी करना।
(D) जिले में न्यायपालिका के प्रमुख के रूप में कार्य करना।

115. मध्य प्रदेश में 'विकास की राजनीति' को चलाने वाला एक प्रमुख कारक है:
(A) चुनाव जीतने के लिए विकास परियोजनाओं का श्रेय लेने हेतु राजनीतिक दलों के बीच प्रतिस्पर्धा।
(B) उच्चतम न्यायालय द्वारा अनिवार्य एक कानूनी आवश्यकता।
(C) राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से राज्य का अलगाव।
(D) किसी भी सामाजिक या आर्थिक समस्या की अनुपस्थिति।

116. स्थायी लोक सेवकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन I: मध्य प्रदेश में सचिवालय का संचालन स्थायी लोक सेवकों द्वारा किया जाता है।
कथन II: सचिवालय का प्राथमिक कार्य उच्च स्तरीय सलाहकार और नीति-निर्माण निकाय के रूप में कार्य करना है, न कि सीधे क्षेत्रीय क्रियान्वयन के लिए।
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
(D) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।

117. मध्य प्रदेश में नक्सलवाद का मुद्दा जटिल है क्योंकि इसमें किसका मिश्रण शामिल है?
(A) आंतरिक सुरक्षा चुनौतियां, सामाजिक-आर्थिक पिछड़ापन और शासन की कमियां।
(B) शहरी प्रदूषण और यातायात की भीड़।
(C) नगर निगमों की वित्तीय स्वायत्तता।
(D) मुख्य सचिव की चयन प्रक्रिया।

118. मध्य प्रदेश में स्थानीय स्वशासन के बारे में कौन सा कथन गलत है?
(A) यह 73वें और 74वें संशोधनों के माध्यम से संवैधानिक रूप से अनिवार्य है।
(B) यह लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर कार्य करता है।
(C) राज्य सरकार पर वित्तीय निर्भरता एक बड़ी चुनौती है।
(D) इसे नौकरशाही सहायता और नियंत्रण से पूरी तरह मुक्त होने के लिए बनाया गया है।

119. मध्य प्रदेश राज्य सरकार में एक महिला का मंत्री बनना किसका उदाहरण है?
(A) स्थानीय स्वशासन की विफलता।
(B) राज्य स्तरीय राजनीति में महिलाओं का योगदान और भागीदारी।
(C) कलेक्टर की एकमात्र जिम्मेदारी।
(D) नक्सली समस्या से संबंधित एक मुद्दा।

120. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:
सूची I: (प्रशासनिक अधिकारी)
P. मुख्य सचिव
Q. आयुक्त
R. कलेक्टर
S. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत
सूची II: (संचालन का प्राथमिक क्षेत्र)
1. जिला
2. राज्य
3. विकास खंड
4. संभाग
(A) P-2, Q-4, R-1, S-3
(B) P-1, Q-2, R-3, S-4
(C) P-2, Q-1, R-4, S-3
(D) P-4, Q-2, R-1, S-3

121. मध्य प्रदेश में स्थानीय स्वशासन संस्थानों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था?
(A) जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक भागीदारी की प्रक्रिया को मजबूत करना।
(B) राज्य की राजधानी में सभी निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को केंद्रित करना।
(C) जिला कलेक्टर के पद को समाप्त करना।
(D) मुख्य सचिव के प्रशासनिक कार्यभार को बढ़ाना।

122. यदि मध्य प्रदेश में एक नगर निगम अपने कचरा निपटान को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में विफल रहता है, जिससे स्वास्थ्य संकट पैदा होता है, तो यह किसकी संभावित विफलता को दर्शाता है?
(A) आवश्यक नागरिक सेवाएं प्रदान करने के लिए संगठन और उसकी शक्तियां।
(B) जनजातीय वर्गों को सशक्त बनाने में भूमिका।
(C) नक्सलवाद से निपटने की रणनीति।
(D) नीतिगत मामलों पर राज्य सचिवालय के साथ संबंध।

123. मध्य प्रदेश की राजनीति में महिलाओं के सशक्तिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण सशक्तिकरण का एक प्रमुख साधन रहा है।
2. राज्य की महिला राजनीतिज्ञों ने कभी भी कोई महत्वपूर्ण कैबिनेट पद नहीं संभाला है।
3. राजनीति में महिलाओं की बढ़ती उपस्थिति ने महिला-केंद्रित मुद्दों को उठाने में मदद की है।
उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) केवल 1 और 3
(B) केवल 2
(C) केवल 2 और 3

Click Here to Buy book on Amazon

कथन II: आयुक्त एक संभाग का प्रमुख होता है, जिसमें कई जिले शामिल होते हैं, और वह उस संभाग के भीतर कलेक्टरों की निगरानी करता है।
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
(D) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।

105. मध्य प्रदेश के एक ग्रामीण क्षेत्र में एक नई विनिर्माण इकाई स्थापित करने का प्रस्ताव नौकरियों का वादा और भूमि अधिग्रहण एवं प्रदूषण का डर दोनों लाता है। सरकार, उद्योग और स्थानीय समुदायों के बीच होने वाली बहस और बातचीत किसका उदाहरण है?
(A) सचिवालय का आंतरिक कामकाज।
(B) विकास की राजनीति।
(C) शहरी स्थानीय स्वशासन का संगठन।
(D) मुख्य सचिव की शक्तियां।

106. मध्य प्रदेश के नक्सलवाद से प्रभावित जिले में कलेक्टर से क्या अपेक्षा की जाएगी?
(A) केवल राजस्व संग्रह पर ध्यान देना और सुरक्षा स्थिति की अनदेखी करना।
(B) पुलिस अधीक्षक के साथ निकटता से समन्वय करना और विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देना।
(C) जिला मुख्यालय को किसी सुरक्षित राज्य में स्थानांतरित करना।
(D) उच्च न्यायालय की न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करना।

107. कौन सा कथन मध्य प्रदेश की राजनीति में महिलाओं के योगदान को सटीक रूप से दर्शाता है?
(A) महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी केवल निष्क्रिय मतदाता होने तक सीमित है।
(B) महिलाओं ने सरपंच से लेकर मुख्यमंत्री तक के पद संभाले हैं, जिससे नीति और शासन प्रभावित हुआ है।
(C) राज्य में महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से कोई विशिष्ट नीति नहीं है।
(D) महिलाओं की भागीदारी का विकास के मुद्दों पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ा है।

108. मध्य प्रदेश की स्थानीय सरकार में नौकरशाही के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. जिला पंचायत का मुख्य कार्यपालन अधिकारी एक नियुक्त लोक सेवक होता है।
2. नौकरशाही परियोजनाओं को लागू करने के लिए आवश्यक तकनीकी और कानूनी विशेषज्ञता प्रदान करती है।
3. नौकरशाही की भूमिका निर्वाचित प्रतिनिधियों के निर्णयों को प्रतिस्थापित करना और उन्हें दरकिनार करना है।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 3
(C) केवल 2 और 3
(D) 1, 2 और 3

109. मध्य प्रदेश में राज्य सचिवालय का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?
(A) राज्य की राजधानी में सभी शक्तियों का केंद्रीकरण।
(B) लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का समर्थन।
(C) वंशानुगत राजतंत्र द्वारा शासन।
(D) सैन्य अधिकारियों द्वारा प्रशासन।

110. निम्नलिखित अभिकथन (A) और कारण (R) पर विचार कीजिए:
अभिकथन (A): मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव के पास महत्वपूर्ण प्रशासनिक अधिकार होते हैं।
कारण (R): सिविल सेवाओं के प्रमुख के रूप में, मुख्य सचिव मंत्री परिषद के निर्णयों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करते हैं और विभागों में प्रशासनिक दक्षता बनाए रखते हैं।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

111. निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश में जिला प्रशासन की सामान्य जिम्मेदारी नहीं है?
(A) भूमि अभिलेखों का रखरखाव।
(B) आपदा प्रबंधन और राहत कार्य।
(C) कानून और व्यवस्था की देखरेख।
(D) राज्य का वार्षिक बजट तैयार करना।

112. मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्गों के सशक्तिकरण पर राजनीतिक विमर्श मुख्य रूप से किससे संबंधित है?
(A) सामाजिक न्याय और समानता प्राप्त करना।
(B) अंतरराष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा देना।
(C) अधिक प्रशासनिक कार्यालयों का निर्माण करना।
(D) मुख्य सचिव के वेतन में वृद्धि करना।

113. मध्य प्रदेश में शहरी स्थानीय निकायों को उनकी बस्ती के आकार के अनुसार सबसे बड़े प्रकार से सबसे छोटे प्रकार के पदानुक्रमित क्रम में व्यवस्थित करें।
1. नगर पालिका परिषद
2. नगर पंचायत
3. नगर निगम

सही क्रम चुनिए:
(A) 2, 1, 3
(B) 3, 1, 2
(C) 1, 2, 3
(D) 3, 2, 1

114. मध्य प्रदेश में "कलेक्टर की भूमिका" में निम्नलिखित में से किसे छोड़कर सभी शामिल हैं?

Downloaded from www.pdf.tube

नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

135. मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं?
(A) भारत के राष्ट्रपति
(B) मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद
(C) भारत के मुख्य न्यायाधीश
(D) प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से राज्य के मतदाता

136. मध्य प्रदेश में कलेक्टर की बहुआयामी भूमिका में वे कार्य शामिल हैं जो:
(A) प्रकृति में विशेष रूप से न्यायिक हैं।
(B) केवल राजस्व संग्रहण से संबंधित हैं।
(C) प्रशासनिक, दंडाधिकारी और विकासात्मक जिम्मेदारियों का मिश्रण हैं।
(D) विशुद्ध रूप से राजनीतिक हैं और जिनके लिए पार्टी संबद्धता आवश्यक है।

137. निम्नलिखित में से कौन 'मध्य प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य' का एक पहलू नहीं है?
(A) जनजातीय और पिछड़े वर्गों का सशक्तिकरण।
(B) नक्सली समस्या से संबंधित मुद्दे।
(C) पड़ोसी देशों के साथ मध्य प्रदेश की विदेश नीति।
(D) राज्य की राजनीति में महिलाओं का योगदान।

138. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:
सूची I: (अवधारणा)
P. विकास की राजनीति
Q. महिलाओं का योगदान
R. कलेक्टर की भूमिका
S. नक्सली मुद्दा
सूची II: (मध्य प्रदेश में उदाहरण)
1. उमा भारती का मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करना
2. एक जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्रियान्वयन
3. बालाघाट जिले में सुरक्षा अभियान
4. चुनाव से पहले किसानों के लिए कर्ज माफी की घोषणा करना
(A) P-4, Q-1, R-2, S-3
(B) P-1, Q-4, R-2, S-3
(C) P-4, Q-2, R-1, S-3
(D) P-3, Q-1, R-2, S-4

139. मध्य प्रदेश में राज्य वित्त आयोग का गठन किसके संबंध में अनुशंसाएं करने के लिए किया जाता है?
(A) राज्य और केंद्र सरकार के बीच वित्तीय संबंध।
(B) वे सिद्धांत जो राज्य और स्थानीय स्वशासन निकायों के बीच निधियों के वितरण को नियंत्रित करेंगे।
(C) विधानसभा के सदस्यों के वेतन।
(D) राज्य में निजी निगमों का वित्तपोषण।

140. मध्य प्रदेश में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के संगठन और शक्तियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. यह एक त्रि-स्तरीय प्रणाली है जिसमें ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत शामिल हैं।
2. इन निकायों को संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों से संबंधित शक्तियाँ और जिम्मेदारियाँ दी गई हैं।
3. इनका नेतृत्व मुख्य सचिव द्वारा नियुक्त अधिकारियों द्वारा किया जाता है।
उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 3
(D) 1, 2 और 3

141. मध्य प्रदेश सचिवालय में सचिव की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन क्या है?
(A) मुख्यमंत्री का निजी सहायक।
(B) सरकार के एक विशिष्ट विभाग का प्रशासनिक प्रमुख और विशेषज्ञ सलाहकार।
(C) किसी मंत्रालय के लिए जिम्मेदार निर्वाचित प्रतिनिधि।
(D) राज्य का मुख्य कानून प्रवर्तन अधिकारी।

142. मध्य प्रदेश की राजनीति में "जनजातीय वर्गों का सशक्तिकरण" शब्द में कौन सा मुख्य मुद्दा शामिल है?
(A) आदिवासियों को चुनाव में भाग लेने से रोकना।
(B) वन संसाधनों पर उनके पारंपरिक अधिकारों को पहचानना और सुरक्षित करना।
(C) सभी आदिवासी आबादी को जबरन शहरों में स्थानांतरित करना।
(D) आदिवासियों के लिए आरक्षण नीतियों को समाप्त करना।

143. मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़क निर्माण को प्राथमिकता देने का निर्णय किस दोहरे उद्देश्य को पूरा करता है?
(A) विकास के लिए संपर्क में सुधार करना और सुरक्षा बलों की आवाजाही को सुगम बनाना।
(B) शहरी प्रदूषण को बढ़ाना और पिछड़े वर्गों को सशक्त बनाना।
(C) स्थानीय स्वशासन को कमजोर करना और कलेक्टर को मजबूत करना।
(D) एक अंतरराष्ट्रीय संधि का पालन करना और महिलाओं की राजनीति में योगदान देना।

144. जिला पंचायत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन I: कलेक्टर जिला पंचायत का मुख्य कार्यपालन अधिकारी होता है।
कथन II: जिला पंचायत का मुख्य कार्यपालन अधिकारी एक अलग सरकारी अधिकारी होता है, जो अक्सर आईएएस

NODIA

(D) 1, 2 और 3

124. निम्नलिखित अभिकथन (A) और कारण (R) पर विचार कीजिए:
अभिकथन (A): मध्य प्रदेश में विकास की राजनीति अक्सर विवादास्पद होती है।
कारण (R): विभिन्न सामाजिक समूह और क्षेत्र सीमित राज्य संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, और विकास संबंधी चुनाव अनिवार्य रूप से विजेताओं और हारने वालों को जन्म देते हैं।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

125. मध्य प्रदेश में जिला कलेक्टर का प्रशासनिक पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है?
(A) सीधे मुख्यमंत्री द्वारा
(B) संभाग के आयुक्त द्वारा
(C) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा
(D) जिला मुख्यालय वाले शहर के महापौर द्वारा

126. मध्य प्रदेश में स्थानीय स्वशासन के ढांचे के भीतर काम करने वाली नौकरशाही के लिए एक प्रमुख चुनौती क्या है?
(A) कानूनों या नियमों की पूरी तरह से अनुपस्थिति।
(B) वित्तीय संसाधनों की अत्यधिक प्रचुरता।
(C) निर्वाचित स्थानीय प्रतिनिधियों के अधिकार के अनुकूल होना और उनके साथ मिलकर काम करना।
(D) करने के लिए किसी काम की कमी।

127. विधान के संबंध में मध्य प्रदेश सचिवालय का प्राथमिक कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है?
(A) विधानसभा में अंतिम कानून पारित करना।
(B) विधायिका में पेश किए जाने वाले सरकारी विधेयकों का मसौदा तैयार करना।
(C) विधायिका द्वारा पारित कानूनों के खिलाफ अपील सुनना।
(D) कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को गिरफ्तार करना।

128. मध्य प्रदेश में राजनीतिक साधनों के माध्यम से वंचित वर्गों के सशक्तिकरण का उद्देश्य क्या है?
(A) उन्हें शासन और नीति निर्माण में आवाज प्रदान करना।
(B) उन्हें शेष जनसंख्या से अलग करना।
(C) उनके मतदान के अधिकार को रद्द करना।
(D) यह सुनिश्चित करना कि वे आर्थिक रूप से निर्भर रहें।

129. नक्सली समस्या के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन I: मध्य प्रदेश में नक्सली समस्या विशेष रूप से इंदौर और भोपाल जैसे प्रमुख शहरी केंद्रों में केंद्रित है।
कथन II: नक्सली समस्या आमतौर पर राज्य के सुदूर, वन और अविकसित सीमावर्ती जिलों से जुड़ी होती है।
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
(D) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।

130. मध्य प्रदेश में शहरों या क्षेत्रों के लिए विशिष्ट विकास प्राधिकरणों की स्थापना किसका उदाहरण है?
(A) विकास की राजनीति।
(B) मुख्य सचिव की भूमिका।
(C) ग्रामीण स्थानीय सरकार की विफलता।
(D) वंचित वर्गों से संबंधित एक मुद्दा।

131. "मध्य प्रदेश में जिला प्रशासन" शब्द मुख्य रूप से किसे संदर्भित करता है?
(A) पूरे राज्य में एक ही सरकारी विभाग का प्रशासनिक ढांचा।
(B) जिला स्तर पर संपूर्ण सरकारी तंत्र और उसके कार्य, जो कलेक्टर के इर्द-गिर्द केंद्रित होते हैं।
(C) केवल जिला अदालत प्रणाली का प्रशासन।
(D) एक जिले के भीतर गैर-सरकारी संगठनों की गतिविधियां।

132. मध्य प्रदेश की एक महिला राजनीतिक नेता द्वारा घरेलू हिंसा के खिलाफ सख्त कानूनों की वकालत करना किसका उदाहरण है?
(A) विधायी एजेंडे को आकार देने में राजनीति में महिलाओं का योगदान।
(B) नौकरशाही के काम में हस्तक्षेप।
(C) शहरी स्थानीय सरकार की विफलता।
(D) नक्सलवाद से संबंधित मुद्दा।

133. निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश में एक स्थानीय सरकारी निकाय को उसके अधिकार क्षेत्र के साथ सही ढंग से जोड़ता है?
(A) ग्राम पंचायत - एक पूरा जिला
(B) नगर निगम - एक बड़ा शहर
(C) जिला पंचायत - एक अकेला गांव
(D) जनपद पंचायत - पूरा राज्य

134. निम्नलिखित अभिकथन (A) और कारण (R) पर विचार कीजिए:
अभिकथन (A): वित्तीय बाधाएं मध्य प्रदेश में शहरी स्थानीय स्वशासन के प्रभावी कामकाज में एक बड़ी बाधा हैं।
कारण (R): कई शहरी निकायों के पास अपना स्वयं का राजस्व जुटाने की सीमित शक्तियां हैं और वे राज्य सरकार के अनुदानों पर अत्यधिक निर्भर हैं, जो अपर्याप्त या विलंबित हो सकते हैं।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या

Click Here to Buy book on Amazon

कारण (R): आवश्यक प्रशासनिक विशेषज्ञता प्रदान करते हुए, नौकरशाही ढांचा कभी-कभी निर्वाचित स्थानीय प्रतिनिधियों के राजनीतिक अधिकार के साथ टकरा सकता है, जिससे घर्षण पैदा होता है।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

57. मध्य प्रदेश में शहरी स्थानीय निकायों के लिए एक बड़ी चुनौती विकास की आवश्यकता के साथ किसका संतुलन बनाना है?
(A) केंद्र सरकार के विदेश नीति उद्देश्य।
(B) पड़ोसी राज्यों का चुनाव कार्यक्रम।
(C) बुनियादी नागरिक सुविधाओं का प्रावधान और वित्तीय स्थिरता।
(D) भारतीय सेना का प्रशासनिक पदानुक्रम।

58. मध्य प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य में जनजातीय वर्गों का सशक्तिकरण संवैधानिक और कानूनी रूप से किन प्रावधानों द्वारा समर्थित है?
(A) पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम (पेसा)।
(B) केवल नगर निगम अधिनियम।
(C) भारतीय विदेश सेवा नियम।
(D) राज्य सचिवालय के उप-नियम।

59. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:
सूची I: (प्रशासनिक पद/इकाई)
P. मुख्य सचिव
Q. संभाग
R. जिला
S. तहसील
सूची II: (विवरण)
1. एक आयुक्त के अधीन जिलों का समूह
2. कलेक्टर के अधीन प्रशासन की मूल इकाई
3. राजस्व प्रशासन के लिए जिले का उप-विभाजन
4. राज्य की सिविल सेवाओं का प्रमुख
(A) P-4, Q-2, R-1, S-3
(B) P-4, Q-1, R-2, S-3
(C) P-1, Q-4, R-2, S-3
(D) P-3, Q-1, R-2, S-4

60. मध्य प्रदेश में मुख्य सचिव की भूमिका में मुख्य रूप से क्या शामिल है?
(A) राज्य पुलिस बल की प्रत्यक्ष कमान।
(B) राजनीतिक कार्यकारिणी और प्रशासनिक तंत्र के बीच मुख्य कड़ी के रूप में कार्य करना।
(C) सभी जिलों से व्यक्तिगत रूप से राजस्व एकत्र करना।
(D) नगर निगम का नेतृत्व करना।

61. कलेक्टर की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन I: मध्य प्रदेश में कलेक्टर के पास चुनाव कराने से संबंधित कोई जिम्मेदारी नहीं है।
कथन II: कलेक्टर, जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में, जिले में संसदीय और विधानसभा चुनावों के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
(D) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।

NODIA

62. मध्य प्रदेश में कुछ जिलों को 'नक्सल प्रभावित' घोषित करने का निर्णय मुख्य रूप से किस पर आधारित है?
(A) औद्योगिक विकास का स्तर।
(B) शहरी क्षेत्रों का जनसंख्या घनत्व।
(C) पंचायतों के लिए चुनी गई महिलाओं की संख्या।
(D) चरमपंथी समूहों की उपस्थिति, गतिविधि और संबंधित हिंसा।

63. मध्य प्रदेश सरकार में एक सचिव और एक मंत्री के बीच के संबंध का सबसे अच्छा वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा है?
(A) सचिव विभाग का प्रशासनिक प्रमुख होता है, जो मंत्री द्वारा निर्धारित नीतियों को लागू करने के लिए जिम्मेदार होता है।
(B) सचिव मंत्री का राजनीतिक प्रमुख होता है।
(C) सचिव और मंत्री के पास समान शक्तियां और जिम्मेदारियां होती हैं।
(D) मंत्री दैनिक प्रशासन के लिए जिम्मेदार होता है, जबकि सचिव राजनीतिक रैलियों पर ध्यान केंद्रित करता है।

64. मध्य प्रदेश की राजनीति में, विशेष रूप से जमीनी स्तर पर, महिलाओं का एक महत्वपूर्ण योगदान क्या रहा है?
(A) विशेष रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों पर ध्यान केंद्रित करना।
(B) स्वच्छता, जल आपूर्ति और शिक्षा जैसे मुद्दों को स्पष्ट करना और उन्हें संबोधित करना।
(C) सभी सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन को रोकना।
(D) राज्य सचिवालय के भीतर सभी शक्तियों का केंद्रीकरण करना।

65. मध्य प्रदेश में स्थानीय स्वशासन वित्त के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. स्थानीय निकाय पूरी तरह से अपने स्वयं के राजस्व पर निर्भर हैं और उन्हें राज्य से कोई धन प्राप्त नहीं होता है।
2. राज्य वित्त आयोग राज्य और स्थानीय निकायों के बीच संसाधनों के वितरण के लिए अनुशंसाएं करता है।
3. पर्याप्त और समय पर धन का हस्तांतरण न होना स्थानीय निकायों के लिए एक बड़ी चुनौती है।
उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) केवल 1

संवर्ग से होता है, जबकि कलेक्टर की अलग और स्वतंत्र जिम्मेदारियां होती हैं।
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
(D) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।

145. मध्य प्रदेश में स्थानीय स्वशासन की स्वायत्तता अक्सर किसके कारण प्रभावित होती है?
(A) राज्य सरकार का अत्यधिक नियंत्रण और उस पर वित्तीय निर्भरता।
(B) स्थानीय स्तर पर हल करने के लिए किसी समस्या की कमी।
(C) स्थानीय स्तर पर उत्पन्न राजस्व की अधिकता।
(D) सभी स्थानीय मामलों में केंद्र सरकार का सीधा हस्तक्षेप।

146. निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश में 'विकास की राजनीति' की एक अभिव्यक्ति है?
(A) सचिवालय कर्मचारियों का दैनिक कार्य रोस्टर।
(B) एक राजनीतिक दल द्वारा अपने चुनावी घोषणा पत्र में किसानों को निःशुल्क बिजली देने का वादा करना।
(C) विधानसभा में स्थगन प्रस्तावों की प्रक्रिया।
(D) एक पुलिस आरक्षक का एक थाने से दूसरे थाने में स्थानांतरण।

147. मध्य प्रदेश के एक शहर के महापौर और नगर निगम आयुक्त के बीच एक प्रमुख शहरी परियोजना पर परस्पर विरोधी विचार शहरी शासन में किसके बीच संभावित तनाव को उजागर करते हैं?
(A) राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका।
(B) ग्रामीण और शहरी स्थानीय स्वशासन।
(C) राज्य सरकार और केंद्र सरकार।
(D) कलेक्टर और मुख्य सचिव।

148. निम्नलिखित अभिकथन (A) और कारण (R) पर विचार कीजिए:
अभिकथन (A): मध्य प्रदेश में पंचायतों में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण उनके राजनीतिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रहा है।
कारण (R): इस नीति ने जमीनी स्तर पर निर्णय लेने वाले निकायों में उनकी उपस्थिति सुनिश्चित की है, हालांकि 'सरपंच पति' संस्कृति जैसी चुनौतियां बनी हुई हैं।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

149. मध्य प्रदेश के किसी जिले में कानून और व्यवस्था बनाए रखने की प्राथमिक जिम्मेदारी किसकी होती है?
(A) मुख्य सचिव
(B) जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक
(C) नगर निगम के महापौर
(D) जिला पंचायत के अध्यक्ष

150. मध्य प्रदेश के प्रशासन में निम्नलिखित भूमिकाओं को उनके विशिष्ट प्रभाव क्षेत्र के आधार पर, राज्यव्यापी से स्थानीय (गांव) तक व्यवस्थित करें।
1. कलेक्टर
2. सरपंच
3. मुख्य सचिव
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत
सही क्रम चुनिए:
(A) 3, 1, 4, 2
(B) 3, 4, 1, 2
(C) 1, 3, 4, 2
(D) 2, 4, 1, 3

151. मध्य प्रदेश प्रशासन में मुख्य सचिव की क्या भूमिका है?
(A) गृह या वित्त जैसे विशिष्ट विभाग के प्रमुख।
(B) राज्यपाल के मुख्य सलाहकार।
(C) राज्य की संपूर्ण सिविल सेवा के प्रमुख और मंत्रिमंडल के सचिव।
(D) राज्य पुलिस बल के प्रमुख।

152. 73वां संविधान संशोधन अधिनियम मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में किन निकायों के संगठन और शक्तियों से संबंधित है?
(A) शहरी स्थानीय स्वशासन
(B) राज्य सचिवालय
(C) ग्रामीण स्थानीय स्वशासन
(D) जिला प्रशासन

153. मध्य प्रदेश में कलेक्टर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. कलेक्टर का कार्यालय आजादी के बाद के युग की रचना है।
2. कलेक्टर राज्य सरकार और जिला प्रशासन के बीच कड़ी के रूप में कार्य करता है।
3. आपदा प्रबंधन में कलेक्टर की कोई भूमिका नहीं है।
उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) केवल 2
(B) केवल 1 और 2
(C) केवल 3
(D) 1, 2 और 3

154. मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों द्वारा चलाए जा रहे उद्यमों के लिए अनुदानित ऋण प्रदान करने वाली सरकारी नीति किसका उपाय है?
(A) व्यापक राजनीतिक एजेंडे के हिस्से के रूप में आर्थिक सशक्तिकरण।
(B) शहरी क्षेत्रों में नक्सली समस्या से निपटना।
(C) सचिवालय की संरचना में सुधार।

Downloaded from www.pdf.tube

(B) कलेक्टर छोटे कद का होता है।
(C) कलेक्टर के पास जिले के भीतर शक्तियों की एक विस्तृत श्रृंखला और महत्वपूर्ण अधिकार होते हैं।
(D) कलेक्टर का प्राथमिक ध्यान सैन्य विजय पर है।

195. मध्य प्रदेश में शहरी स्थानीय स्वशासन का नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में संगठन किस पर आधारित है?
(A) बस्ती की जनसंख्या और शहरी स्वरूप।
(B) क्षेत्र की प्रमुख जाति।
(C) राज्य की राजधानी से निकटता।
(D) जिला कलेक्टर का निर्णय।

196. निम्नलिखित अभिकथन (A) और कारण (R) पर विचार कीजिए:
अभिकथन (A): मध्य प्रदेश में स्थानीय स्वशासन के कामकाज के लिए नौकरशाही अपरिहार्य है।
कारण (R): निर्वाचित प्रतिनिधियों में अक्सर प्रशासन चलाने के लिए तकनीकी, वित्तीय और कानूनी ज्ञान की कमी होती है, जिसे पेशेवर अधिकारियों द्वारा पूरा किया जाता है।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

197. मध्य प्रदेश में किस प्रकार के क्षेत्रों में नक्सलवाद की समस्या सबसे प्रमुख है?
(A) घनी आबादी वाले शहरी केंद्र
(B) व्यावसायिक रूप से विकसित औद्योगिक क्षेत्र
(C) सुदूर, वन और अविकसित आदिवासी बहुल क्षेत्र
(D) मालवा क्षेत्र के उपजाऊ कृषि मैदान

198. मध्य प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य में 'पिछड़े वर्गों का सशक्तिकरण' मुख्य रूप से किसे दूर करने पर केंद्रित है?
(A) राजधानी से भौगोलिक दूरी।
(B) ऐतिहासिक सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन।
(C) अंतरराष्ट्रीय मामलों में रुचि की कमी।
(D) आधुनिक तकनीक की चुनौतियाँ।

199. निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश की राजनीति में महिलाओं का प्रत्यक्ष योगदान है?
(A) सरकारी छुट्टियों की संख्या में वृद्धि।
(B) महिलाओं की सुरक्षा और संपत्ति के अधिकारों से संबंधित कानूनों के लिए सफल पैरवी और उन्हें पारित करना।
(C) जिला कलेक्टर के कार्यालय का उन्मूलन।
(D) राज्य के बजट में कमी।

200. मध्य प्रदेश प्रशासन में एक सचिव और एक आयुक्त के बीच का संबंध आम तौर पर क्या होता है?
(A) सचिव राज्य स्तरीय नीति संभालता है, जबकि आयुक्त बहु-जिला क्षेत्र में प्रशासन की देखरेख करता है।
(B) आयुक्त सचिव से वरिष्ठ होता है।
(C) दोनों पद समान और विनिमेय हैं।
(D) सचिव क्षेत्रीय अधिकारी होता है, और आयुक्त सचिवालय में पदस्थ होता है।

201. मध्य प्रदेश में राज्य स्तर पर कौन सा निकाय 'कैबिनेट सचिवालय' के रूप में कार्य करता है, जिसका प्रमुख मुख्य सचिव होता है?
(A) जिला पंचायत
(B) भोपाल नगर निगम
(C) राज्य सचिवालय
(D) आयुक्त कार्यालय

202. मध्य प्रदेश में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन निकायों का वित्तीय स्वास्थ्य उनकी किस क्षमता के लिए महत्वपूर्ण है?
(A) अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में संलग्न होना।
(B) उन्हें सौंपे गए कार्यों को करना, जैसे स्थानीय संपत्तियों का रखरखाव और योजनाओं का क्रियान्वयन।
(C) मुख्य सचिव की नियुक्ति करना।
(D) उच्च न्यायालय के अधिकार को चुनौती देना।

203. मध्य प्रदेश में 'विकास की राजनीति' के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. इसमें राजनीतिक वैधता और चुनावी समर्थन हासिल करने के लिए विकास को एक उपकरण के रूप में उपयोग करना शामिल है।
2. निर्णय हमेशा विशुद्ध रूप से तर्कसंगत और तकनीकी मानदंडों पर आधारित होते हैं, जो राजनीतिक प्रभाव से रहित होते हैं।
3. इससे संसाधनों को लेकर विभिन्न क्षेत्रों और समुदायों के बीच प्रतिस्पर्धा और संघर्ष हो सकता है।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) केवल 1 और 3
(B) केवल 2
(C) केवल 2 और 3
(D) 1, 2 और 3

204. मध्य प्रदेश के नक्सलवाद से प्रभावित जिले में, कलेक्टर की प्राथमिक चुनौती क्या है?
(A) शहरी क्षेत्रों में संपत्ति कर संग्रहण बढ़ाना।
(B) सुशासन और विकास की पहुंच सुनिश्चित करके स्थानीय आबादी का विश्वास जीतना।
(C) सांस्कृतिक उत्सवों का आयोजन करना।
(D) एक नए सचिवालय भवन के निर्माण की देखरेख करना।

205. निम्नलिखित अभिकथन (A) और कारण (R) पर विचार कीजिए:
अभिकथन (A): मध्य प्रदेश में कलेक्टर भूमि अभिलेखों के रखरखाव के लिए जिम्मेदार है।

NODIA

165. मध्य प्रदेश में ग्राम विकास योजना को लागू करने में एक ग्राम पंचायत की सफलता निम्नलिखित में से किस पर सबसे कम निर्भर है?
(A) धन की उपलब्धता।
(B) ग्रामीणों का सहयोग।
(C) सरपंच का नेतृत्व।
(D) राज्य की विदेशी निवेश नीति।

166. मध्य प्रदेश में शहरी स्थानीय स्वशासन में नौकरशाही की एक महत्वपूर्ण भूमिका क्या है?
(A) महापौर के खिलाफ चुनाव लड़ना।
(B) यह सुनिश्चित करना कि निर्वाचित परिषद द्वारा लिए गए निर्णय नियमों और विनियमों के अनुसार लागू किए जाएं।
(C) अपना स्वयं का राजनीतिक घोषणापत्र तैयार करना।
(D) सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय को रिपोर्ट करना।

167. मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. मुख्य सचिव एक राजनीतिक दल का प्रमुख होता है।
2. मुख्य सचिव प्रशासनिक मामलों पर मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार होता है।
3. मुख्य सचिव का कार्यालय अन्य सभी सचिवों के कार्य का समन्वय करता है।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) केवल 1
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 1 और 3
(D) 1, 2 और 3

168. मध्य प्रदेश में "विकास की राजनीति" तब स्पष्ट होती है जब:
(A) एक सरकारी फाइल को एक पटल से दूसरे पटल पर ले जाया जाता है।
(B) सत्तारूढ़ दल चुनाव से ठीक पहले एक बड़े पुल या कारखाने का उद्घाटन करता है।
(C) अदालत दीवानी विवाद में निर्णय सुनाती है।
(D) मौसम का पूर्वानुमान घोषित किया जाता है।

169. निम्नलिखित अभिकथन (A) और कारण (R) पर विचार कीजिए:
अभिकथन (A): वंचित वर्गों का सशक्तिकरण मध्य प्रदेश के राजनीतिक विमर्श में एक केंद्रीय विषय है।
कारण (R): ये वर्ग मतदाता सूची का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, और सामाजिक न्याय एवं विकास के लिए उनकी चिंताओं को दूर करना राजनीतिक दलों के लिए महत्वपूर्ण है।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

170. मध्य प्रदेश में ग्राम स्तर पर सार्वजनिक निर्माण, स्वच्छता और प्राथमिक शिक्षा के संबंध में निर्णय लेने के लिए कौन सा निकाय जिम्मेदार है?
(A) राज्य सचिवालय
(B) जिला कलेक्टर कार्यालय
(C) ग्राम पंचायत
(D) नगर निगम

171. मध्य प्रदेश के एक प्रमुख शहर की महापौर के रूप में एक महिला का चुना जाना किसका महत्वपूर्ण संकेतक है?
(A) शहरी राजनीति में महिलाओं की बढ़ती भूमिका और योगदान।
(B) ग्रामीण स्थानीय स्वशासन प्रणाली की पूर्ण विफलता।
(C) नक्सली समस्या का समाधान।
(D) सचिवालय की संरचना में सुधार।

172. मध्य प्रदेश में जिला स्तर पर एक समन्वयक के रूप में कलेक्टर की भूमिका किसके लिए आवश्यक है?
(A) विभिन्न सरकारी विभागों के बीच प्रयासों के दोहराव और संघर्षों को रोकना।
(B) उच्चतम न्यायालय में मामलों का फैसला करना।
(C) राष्ट्रीय आर्थिक नीति तैयार करना।
(D) व्यक्तिगत रूप से सड़कों और इमारतों का निर्माण करना।

173. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:
सूची I: (प्रशासनिक स्तर)
P. राज्य स्तर
Q. संभागीय स्तर
R. जिला स्तर
S. ग्राम स्तर
सूची II: (मुख्य अधिकारी/निकाय)
1. आयुक्त
2. कलेक्टर
3. ग्राम पंचायत
4. मुख्य सचिव
(A) P-4, Q-1, R-2, S-3
(B) P-1, Q-4, R-2, S-3
(C) P-4, Q-2, R-1, S-3
(D) P-3, Q-1, R-2, S-4

174. मध्य प्रदेश में एक नगर निगम के लिए 'स्वायत्तता' की अवधारणा का तात्पर्य उसकी किस क्षमता से है?
(A) राज्य से स्वतंत्रता की घोषणा करना।
(B) कानूनी ढांचे के भीतर, स्थानीय मामलों पर अपने निर्णय लेना और अपना स्वयं का धन जुटाना।
(C) जिला कलेक्टर के सभी आदेशों की अवज्ञा करना।
(D) अपनी समानांतर न्यायिक प्रणाली बनाना।

Click Here to Buy book on Amazon

(C) ब्रिटिश राजतंत्र में उत्तराधिकार के नियम।
(D) विशिष्ट समूहों के लिए सामाजिक कल्याण योजनाओं की घोषणा।

216. मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में एक महिला की नियुक्ति किसके लिए एक ऐतिहासिक घटना होगी?
(A) ग्रामीण जनता का सशक्तिकरण।
(B) राज्य प्रशासन के शीर्ष पर महिलाओं का योगदान।
(C) स्थानीय निकायों की वित्तीय स्वायत्तता।
(D) पिछड़े क्षेत्रों में विकास की राजनीति।

217. निम्नलिखित प्रशासनिक कार्यों को तार्किक अनुक्रम में व्यवस्थित करें।
1. कलेक्टर जिला स्तर की बैठक में विकास योजना की प्रगति की समीक्षा करता है।
2. सचिवालय की सलाह पर राज्य मंत्रिमंडल द्वारा एक नीतिगत निर्णय लिया जाता है।
3. ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर योजना के लाभार्थियों की पहचान करती है।
4. आयुक्त कार्यालय संभाग के कलेक्टरों को राज्य की नीति से अवगत कराता है।

सही क्रम चुनिए:
(A) 2, 4, 1, 3
(B) 1, 2, 3, 4
(C) 2, 1, 4, 3
(D) 4, 2, 1, 3

218. मध्य प्रदेश के स्थानीय स्वशासन में नौकरशाही और निर्वाचित प्रतिनिधियों के बीच के संबंध को सबसे अच्छा वर्णित किया जा सकता है:
(A) अस्तित्वहीन के रूप में।
(B) विशुद्ध रूप से पदानुक्रमित, जिसमें नौकरशाही हमेशा कमान में रहती है।
(C) सहजीवी लेकिन घर्षण के प्रति संवेदनशील, जिसमें नौकरशाही निष्पादन एवं विशेषज्ञता प्रदान करती है और प्रतिनिधि लोकतांत्रिक वैधता प्रदान करते हैं।
(D) हमेशा सामंजस्यपूर्ण और बिना किसी संघर्ष के।

219. निम्नलिखित अभिकथन (A) और कारण (R) पर विचार कीजिए:
अभिकथन (A): मध्य प्रदेश का मुख्य सचिव सभी सचिवों का प्रमुख होता है।
कारण (R): वह सचिवों की बैठकों की अध्यक्षता करता है और प्रशासनिक पदानुक्रम का प्रमुख होता है, जो सभी विभागों के बीच समन्वय सुनिश्चित करता है।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

220. मध्य प्रदेश के एक नगर निगम को यातायात सुगम बनाने के लिए एक नया फ्लाईओवर बनाने की आवश्यकता है। परियोजना की सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारक है?
(A) इसके स्वयं के वित्तीय संसाधन और राज्य से समय पर अनुदान।
(B) एक सुदूर गांव के सरपंच की राय।
(C) एक पड़ोसी देश की राजनीतिक स्थिति।
(D) सचिवालय की प्रशासनिक संरचना।

221. मध्य प्रदेश में जिला मजिस्ट्रेट के रूप में कलेक्टर की भूमिका में क्या शामिल है?
(A) राजस्व का संग्रहण।
(B) जिले के आपराधिक न्याय प्रशासन की अध्यक्षता करना और कानून-व्यवस्था बनाए रखना।
(C) सड़कों और इमारतों का निर्माण।
(D) ग्रामीण विकास योजनाओं को लागू करना।

222. मध्य प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. जनजातीय, पिछड़े और वंचित वर्गों का सशक्तिकरण महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दे हैं।
2. राज्य नक्सलवाद जैसी किसी भी आंतरिक सुरक्षा चुनौती से पूरी तरह मुक्त है।
3. राजनीति में महिलाओं का योगदान राज्य के राजनीतिक जीवन का एक स्वीकृत पहलू है।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) केवल 1 और 3
(B) केवल 2
(C) केवल 2 और 3
(D) 1, 2 और 3

223. मध्य प्रदेश में 'विकास की राजनीति' सीधे तौर पर किससे जुड़ी हुई है?
(A) आर्थिक संसाधनों और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के आवंटन पर राज्य का नियंत्रण।
(B) संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का कामकाज।
(C) प्राथमिक विद्यालयों का पाठ्यक्रम।
(D) न्यायपालिका के भीतर पदोन्नति नीति।

224. मध्य प्रदेश सरकार में एक सचिव और एक मंत्री के बीच एक प्रमुख अंतर यह है कि:
(A) सचिव निर्वाचित होता है, और मंत्री नियुक्त होता है।
(B) सचिव एक स्थायी सिविल सेवक होता है, जबकि मंत्री एक अस्थायी, राजनीतिक कार्यपालिका होता है।
(C) सचिव के पास मंत्री की तुलना में अधिक राजनीतिक शक्ति होती है।
(D) कोई अंतर नहीं है; दोनों पद विनिमेय हैं।

225. मध्य प्रदेश में पंचायती राज की स्थापना किसकी ओर एक कदम था?

NODIA

185. निम्नलिखित अभिकथन (A) और कारण (R) पर विचार कीजिए:
अभिकथन (A): कलेक्टर मध्य प्रदेश में जिला प्रशासन के मुख्य आधार के रूप में कार्य करता है।
कारण (R): कलेक्टर का कार्यालय राजस्व संग्रहण और कानून-व्यवस्था से लेकर विकास गतिविधियों के समन्वय तक व्यापक जिम्मेदारियां रखता है, जो इसे जिले में शासन का केंद्र बिंदु बनाता है।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

186. निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति आमतौर पर मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत में निहित नहीं है?
(A) प्राथमिक विद्यालयों का पर्यवेक्षण।
(B) गांव की सड़कों और कुओं का रखरखाव।
(C) गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का क्रियान्वयन।
(D) राज्य का वार्षिक बजट पारित करना।

187. मध्य प्रदेश में प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. मुख्य सचिव राज्य का राजनीतिक प्रमुख होता है।
2. सचिव एक सरकारी विभाग का प्रशासनिक प्रमुख होता है।
3. आयुक्त जिलों के एक समूह के प्रशासन की देखरेख करता है।
उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 3
(D) 1, 2 और 3

188. पेशेवर प्रशासन और निर्वाचित प्रतिनिधियों के जनादेश के बीच तनाव किसके अध्ययन में एक आवर्ती विषय है?
(A) विकास की राजनीति।
(B) नक्सली समस्या।
(C) मध्य प्रदेश में स्थानीय स्वशासन।
(D) मुख्य सचिव की भूमिका।

189. मध्य प्रदेश में एक नया जिला बनाने की मांग के लिए आयोजित राजनीतिक रैली किसका उदाहरण है?
(A) एक नियमित सचिवालय कार्य।
(B) प्रशासनिक और विकासात्मक सीमाओं के इर्द-गिर्द की राजनीति।
(C) शहरी स्थानीय सरकार की एक बैठक।
(D) राजनीति में महिलाओं का योगदान।

190. मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्गों के राजनीतिक सशक्तिकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है?
(A) यह सुनिश्चित करना कि सत्ता की संरचनाओं में उनका प्रतिनिधित्व और आवाज हो।
(B) उनके लिए एक अलग राज्य बनाना।
(C) शिक्षा तक उनकी पहुंच को सीमित करना।
(D) स्थानीय स्वशासन प्रणाली को समाप्त करना।

191. निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश में जिला प्रशासन का सबसे अच्छा विवरण है?
(A) महापौर और नगर परिषद का कार्यालय।
(B) जिला स्तर पर शासन का संपूर्ण संस्थागत ढांचा, जिसका नेतृत्व कलेक्टर करता है।
(C) जिला न्यायाधीश के अधीन न्यायिक प्रशासन।
(D) मुख्यमंत्री सचिवालय का एक शाखा कार्यालय।

192. पंचायतों में महिला प्रतिनिधित्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन I: मध्य प्रदेश में पंचायतों में निर्वाचित होने वाली महिलाओं को अक्सर प्रशिक्षण की कमी और पुरुष रिश्तेदारों के हस्तक्षेप जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
कथन II: चुनौतियों के बावजूद, उनकी भागीदारी से ग्राम स्तर पर स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता जैसे मुद्दों पर अधिक ध्यान दिया गया है।
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
(D) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।

193. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:
सूची I: (पद/अवधारणा)
P. सचिवालय
Q. स्वायत्तता (स्थानीय सरकार)
R. वंचित वर्ग
S. विकास की राजनीति
सूची II: (सर्वोत्तम विवरण)
1. ऐतिहासिक रूप से सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार का सामना करने वाले समूह
2. राजनीतिक लाभ के लिए विकास परियोजनाओं का उपयोग
3. राज्य प्रशासन का तंत्रिका केंद्र
4. कानूनी ढांचे के भीतर स्थानीय निकायों के लिए कार्यात्मक स्वतंत्रता
(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-3, Q-4, R-1, S-2
(C) P-3, Q-1, R-4, S-2
(D) P-4, Q-3, R-2, S-1

194. मध्य प्रदेश में कलेक्टर की भूमिका को अक्सर 'छोटा नेपोलियन' कहा जाता है। इसका तात्पर्य है:
(A) कलेक्टर के पास बिना किसी जवाबदेही के तानाशाही शक्तियाँ हैं।

NODIA

236. मध्य प्रदेश में जिला प्रशासन के मुख्य समन्वयक के रूप में कलेक्टर से क्या अपेक्षा की जाती है?
(A) जिले के सभी विभागों और एजेंसियों को विकास और कल्याण के सामान्य लक्ष्यों की ओर ले जाना।
(B) केवल पुलिस विभाग पर ध्यान देना।
(C) राज्य सरकार के प्रतिद्वंद्वी के रूप में कार्य करना।
(D) महापौर के पद के लिए चुनाव लड़ना।

237. मध्य प्रदेश में पंचायती राज की त्रि-स्तरीय प्रणाली में शामिल हैं:
(A) ग्राम पंचायत, तालुक पंचायत, जिला पंचायत।
(B) ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत।
(C) ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत।
(D) पंचायत, नगर पालिका, निगम।

238. मध्य प्रदेश में नौकरशाही और स्थानीय स्वशासन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. नौकरशाही का उद्देश्य स्थानीय निकायों की सहायता करने के बजाय उन पर नियंत्रण करने के लिए राज्य का एक उपकरण होना है।
2. जिला पंचायत का मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अध्यक्ष और राज्य सरकार दोनों के प्रति जवाबदेह होता है।
3. पूर्ण सामंजस्य और किसी भी घर्षण की अनुपस्थिति अधिकारियों और निर्वाचित सदस्यों के बीच संबंधों की पहचान है।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) केवल 2
(B) केवल 1 और 2
(C) केवल 3
(D) 1, 2 और 3

239. राज्य सचिवालय का राज्य सरकार के साथ वही संबंध है जो कैबिनेट सचिवालय का किसके साथ है:
(A) जिला प्रशासन
(B) केंद्र सरकार
(C) नगर निगम
(D) जिला पंचायत

240. मध्य प्रदेश में कलेक्टर की भूमिका किसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है?
(A) राजनीतिक जनादेश वाला एक निर्वाचित अधिकारी।
(B) क्षेत्र विशेषज्ञ, जो अपने पूरे करियर में एक ही जिले में रहता है।
(C) विभिन्न प्रकार के कार्यों वाला एक सामान्यज्ञ प्रशासक।
(D) बिना किसी कार्यकारी जिम्मेदारी वाला एक न्यायिक अधिकारी।

241. मध्य प्रदेश में जनजातीय समुदायों के राजनीतिक सशक्तिकरण का एक प्रमुख घटक किसका क्रियान्वयन है?
(A) शहरी विकास योजनाएं।
(B) पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम (पेसा)।
(C) नगर निगम अधिनियम।
(D) राज्य की औद्योगिक नीति।

242. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:
सूची I: (निकाय)
P. सचिवालय
Q. जनपद पंचायत
R. नगर निगम
S. जिला प्रशासन
सूची II: (सरकार का स्तर)
1. जिला
2. ब्लॉक/मध्यवर्ती
3. राज्य
4. शहरी स्थानीय
(A) P-3, Q-2, R-4, S-1
(B) P-1, Q-2, R-3, S-4
(C) P-3, Q-4, R-2, S-1
(D) P-4, Q-3, R-1, S-2

243. मध्य प्रदेश में 'विकास की राजनीति' तब तनाव पैदा कर सकती है जब कोई परियोजना एक क्षेत्र को लाभ पहुँचाती है:
(A) जबकि दूसरे क्षेत्र की उपेक्षा की जा रही हो।
(B) और साथ ही अन्य सभी क्षेत्रों को समान रूप से लाभ पहुँचाती हो।
(C) बिना किसी राजनीतिक संलिप्तता के।
(D) न्यायिक आदेश के आधार पर।

244. राज्य नेतृत्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन I: मुख्य सचिव मध्य प्रदेश में मंत्री परिषद का प्रमुख होता है।
कथन II: मुख्यमंत्री मंत्री परिषद का प्रमुख होता है, और मुख्य सचिव राज्य की प्रशासनिक मशीनरी का प्रमुख होता है।
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
(D) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।

245. मध्य प्रदेश में स्थानीय स्वशासन की पूर्ण स्वायत्तता में एक प्राथमिक बाधा क्या है?
(A) उनकी धन व्यय करने में असमर्थता।
(B) वित्तीय संसाधनों और प्रशासनिक कर्मियों के लिए राज्य सरकार पर उनकी निर्भरता।
(C) उनके अस्तित्व पर संवैधानिक प्रतिबंध।
(D) संबोधित करने के लिए किसी स्थानीय मुद्दे की कमी।

246. मध्य प्रदेश के नगर निगमों में समितियों के अध्यक्ष के रूप में महिलाओं की उपस्थिति किसका एक पहलू है?
(A) नक्सली समस्या।

Downloaded from www.pdf.tube

कारण (R): यह भूमिका ब्रिटिश काल की विरासत है जब कलेक्टर मुख्य रूप से राजस्व संग्रहण करने वाला अभिकर्ता होता था, और इस कार्य के लिए सटीक भूमि अभिलेख बनाए रखना आवश्यक था।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

206. निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश में एक वंचित वर्ग के लिए 'sashaktikaran' की अवधारणा का प्रतिनिधित्व करता है?
(A) समुदाय का एक सदस्य विधायक के रूप में चुना जाना और विधानसभा में समुदाय से संबंधित मुद्दों को उठाना।
(B) समुदाय को दान दिया जाना, लेकिन इसके उपयोग में उनकी कोई राय न होना।
(C) समुदाय को राज्य छोड़ने के लिए कहा जाना।
(D) समुदाय को राजनीतिक भागीदारी से वंचित करना।

207. मध्य प्रदेश में पंचायतों में महिला प्रतिनिधियों का एक महत्वपूर्ण योगदान क्या रहा है?
(A) आंगनवाड़ी सेवाओं और स्कूल के मध्याह्न भोजन जैसे मुद्दों को प्राथमिकता देना और उनकी निगरानी करना।
(B) विशेष रूप से केवल कर संग्रहण पर ध्यान देना।
(C) पंचायत प्रणाली को भंग करने की मांग करना।
(D) राज्य सरकार से कम धन की वकालत करना।

208. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:
सूची I: (सरकार का स्तर)
P. ग्रामीण स्थानीय
Q. शहरी स्थानीय
R. जिला
S. राज्य
सूची II: (प्रशासनिक विशेषता)
1. सचिवालय
2. कलेक्टर
3. महापौर/अध्यक्ष
4. सरपंच/प्रधान
(A) P-4, Q-3, R-2, S-1
(B) P-1, Q-2, R-3, S-4
(C) P-4, Q-3, R-1, S-2
(D) P-3, Q-4, R-2, S-1

209. मध्य प्रदेश में स्थानीय स्वशासन निकायों की "स्वायत्तता" को आलोचकों द्वारा किसके कारण अक्सर एक 'मिथक' के रूप में वर्णित किया जाता है?
(A) कर लगाने और कानून बनाने की अत्यधिक शक्तियां।
(B) राज्य पर मजबूत वित्तीय निर्भरता और राज्य द्वारा प्रतिनियुक्त अधिकारियों की शक्ति।
(C) उनके कामकाज में जनहित की पूरी तरह से कमी।
(D) अशिक्षित प्रतिनिधियों का चुनाव।

210. मध्य प्रदेश सरकार में एक सचिव की भूमिका क्या है?
(A) विभाग का राजनीतिक प्रमुख होना।
(B) मंत्री को निरंतरता और विशेषज्ञ सलाह प्रदान करना, जो राजनीतिक प्रमुख होता है।
(C) किसी जिले में सीधे पुलिस बलों की कमान संभालना।
(D) जिला पंचायत की बैठकों की अध्यक्षता करना।

NODIA

211. मध्य प्रदेश के जिला प्रशासन में कलेक्टर की स्थिति का सबसे सटीक वर्णन कौन सा कथन करता है?
(A) बिना किसी वास्तविक शक्ति के एक औपचारिक प्रमुख।
(B) विशेष रूप से केवल न्यायिक कार्यों के लिए जिम्मेदार अधिकारी।
(C) जिले में सभी सरकारी कार्यों के लिए मुख्य कार्यकारी और समन्वयकारी प्राधिकारी।
(D) जनता का एक निर्वाचित प्रतिनिधि।

212. स्थानीय स्वशासन संरचनाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन I: मध्य प्रदेश में ग्रामीण और शहरी स्थानीय स्वशासन का संगठन एक समान है, उनकी संरचना या कार्यों में कोई अंतर नहीं है।
कथन II: ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय अलग-अलग संस्थाएं हैं, जो अलग-अलग अधिनियमों द्वारा शासित हैं और क्रमशः ग्रामीण और शहरी आबादी की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं।
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
(D) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।

213. मध्य प्रदेश में नक्सली समस्या को एक राजनीतिक मुद्दा माना जाता है क्योंकि:
(A) यह राज्य के प्राधिकार को चुनौती देता है और इसमें शासन, विकास एवं अधिकारों के प्रश्न शामिल हैं।
(B) नक्सली चुनाव में भाग लेते हैं और जीतते हैं।
(C) यह राज्य सचिवालय तक सीमित एक समस्या है।
(D) यह राज्य सरकार के लिए राजस्व का एक बड़ा स्रोत है।

214. मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण बढ़ाने का राजनीतिक निर्णय किसका उदाहरण है?
(A) वंचित वर्गों के लिए सशक्तिकरण की राजनीति।
(B) नक्सलवाद से निपटने का एक उपाय।
(C) शहरी स्थानीय सरकार में एक सुधार।
(D) कलेक्टर का नियमित कार्य।

215. मध्य प्रदेश में 'विकास की राजनीति' का संबंध निम्नलिखित में से किससे सबसे कम है?
(A) सिंचाई परियोजनाओं के लिए बजट का आवंटन।
(B) एक नए औद्योगिक गलियारे का स्थान।

175. मध्य प्रदेश में नक्सली समस्या का मुकाबला करने के लिए सरकार की रणनीति में आमतौर पर किसका संयोजन शामिल होता है?
(A) शहरी स्वशासन और अंतरराष्ट्रीय कूटनीति को बढ़ावा देना।
(B) सुरक्षा बल अभियान और सामाजिक-आर्थिक विकास पहल।
(C) सचिवालय में सुधार और अप्रभावित क्षेत्रों में पिछड़े वर्गों को सशक्त बनाना।
(D) स्थानीय निकायों की वित्तीय स्वायत्तता और महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाना।

176. निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश सचिवालय का सबसे सटीक विवरण है?
(A) भोपाल में एक एकल इमारत।
(B) राज्य सरकार के विभागों का वह समूह, जिसका नेतृत्व सचिव करते हैं और जो मंत्रियों की सहायता करता है।
(C) सभी जिला कलेक्टर कार्यालयों के लिए एक सामूहिक शब्द।
(D) विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों का निकाय।

177. मध्य प्रदेश की राजनीति में पेसा जैसे तंत्रों के माध्यम से जनजातीय समुदायों के राजनीतिक सशक्तिकरण का उद्देश्य क्या है?
(A) उन्हें उनके क्षेत्रों में सामुदायिक संसाधनों और शासन पर नियंत्रण देना।
(B) बेहतर रोजगार के लिए उन्हें शहरी केंद्रों में स्थानांतरित करना।
(C) उन्हें राज्य के चुनावों में भाग लेने से अयोग्य घोषित करना।
(D) उनकी सांस्कृतिक परंपराओं को समाप्त करना।

178. जिला कलेक्टर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन I: मध्य प्रदेश में जिला कलेक्टर मुख्य रूप से एक न्यायिक अधिकारी होता है जिसके पास कोई प्रशासनिक कार्य नहीं होता है।
कथन II: कलेक्टर की भूमिका बहुआयामी है, जिसमें राजस्व, दंडाधिकारी, कार्यकारी और विकासात्मक कार्य शामिल हैं।
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
(D) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।

179. मध्य प्रदेश में एक स्थिति जहाँ एक नगर निगम राज्य सरकार से धन की कमी के कारण अपने स्वच्छता कर्मचारियों को वेतन देने में असमर्थ है, किससे संबंधित समस्या का एक बड़ा उदाहरण है?
(A) नक्सली मुद्दा।
(B) स्थानीय स्वशासन में वित्तीय स्वायत्तता की कमी।
(C) मुख्य सचिव की भूमिका।
(D) जनजातीय वर्गों का सशक्तिकरण।

180. मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को मुख्यमंत्री द्वारा वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के पैनल में से चुना जाता है। यह कार्रवाई किसके कामकाज का हिस्सा है?
(A) राज्य की कार्यकारी और प्रशासनिक मशीनरी।
(B) ग्रामीण स्थानीय स्वशासन।
(C) शहरी स्थानीय स्वशासन।
(D) न्यायिक प्रणाली।

181. मध्य प्रदेश में वंचित वर्गों के सशक्तिकरण के लिए एक प्रमुख चुनौती क्या है?
(A) कल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी और भ्रष्टाचार मुक्त क्रियान्वयन।
(B) उनके वोटों में रुचि रखने वाले किसी भी राजनीतिक दल की कमी।
(C) वर्तमान सामाजिक संरचना से उनकी पूर्ण संतुष्टि।
(D) सामाजिक अस्थिरता पैदा करने वाला अत्यधिक सशक्तिकरण।

182. मध्य प्रदेश में निम्नलिखित प्रशासनिक पदों को वरिष्ठता और अधिकार के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें।
1. मुख्य सचिव
2. सचिव
3. कलेक्टर
4. आयुक्त
सही क्रम चुनिए:
(A) 1, 2, 4, 3
(B) 1, 4, 2, 3
(C) 4, 1, 2, 3
(D) 1, 2, 3, 4

183. मध्य प्रदेश के संदर्भ में 'विकास की राजनीति' शब्द का अर्थ है कि कैसे:
(A) विकास संबंधी निर्णय राजनीतिक उद्देश्यों से प्रभावित होते हैं और उनके लिए उपयोग किए जाते हैं।
(B) सारा विकास बिना किसी राजनीतिक हस्तक्षेप के किया जाता है।
(C) केवल राजनेताओं को ही इंजीनियर और डॉक्टर बनने की अनुमति है।
(D) विकास का राजनीति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

184. मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत की एक महिला सरपंच द्वारा अपने गांव में पूर्ण स्वच्छता के लिए अभियान का नेतृत्व करना किसका सशक्त उदाहरण है?
(A) जमीनी स्तर की राजनीति और शासन में महिलाओं का योगदान।
(B) जिला पंचायत की अप्रासंगिकता।
(C) राज्य सचिवालय की वित्तीय शक्ति।
(D) जिला कलेक्टर का प्राथमिक कार्य।

Click Here to Buy book on Amazon

(A) जिला कलेक्टर को मजबूत करना।
(B) 'ग्राम स्वराज' के स्वप्न को साकार करना और सत्ता का विकेंद्रीकरण करना।
(C) मुख्य सचिव के हाथों में सभी शक्तियों को केंद्रित करना।
(D) राज्य विधायिका को समाप्त करना।

226. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:
सूची I: (पद)
P. मुख्य सचिव
Q. महापौर
R. कलेक्टर
S. सरपंच
सूची II: (संबद्ध क्षेत्र)
1. गांव
2. जिला
3. राज्य
4. शहर
(A) P-3, Q-4, R-2, S-1
(B) P-1, Q-2, R-3, S-4
(C) P-3, Q-2, R-4, S-1
(D) P-4, Q-3, R-1, S-2

227. मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत की स्वायत्तता सबसे प्रत्यक्ष रूप से किसके माध्यम से व्यक्त होती है?
(A) हैंडपंप के स्थान या गांव की सड़क की मरम्मत पर निर्णय लेने की क्षमता।
(B) दूसरे गांव के खिलाफ युद्ध की घोषणा करने की शक्ति।
(C) राज्य के मुख्य सचिव की नियुक्ति करने का अधिकार।
(D) भारतीय संविधान की अवहेलना करने का अधिकार।

228. मध्य प्रदेश में 'नक्सली समस्या' केवल सुरक्षा का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह एक:
(A) पर्यटन राजस्व का प्रमुख स्रोत है।
(B) तीव्र शहरीकरण का परिणाम है।
(C) विकास और शासन की चुनौती है।
(D) स्थानीय स्वशासन द्वारा पैदा की गई समस्या है।

229. कलेक्टर की नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन I: मध्य प्रदेश में कलेक्टर की नियुक्ति जिले के सभी नागरिकों द्वारा सीधे चुनाव के माध्यम से की जाती है।
कथन II: कलेक्टर भारतीय प्रशासनिक सेवा या राज्य प्रशासनिक सेवा का सदस्य होता है और राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है।
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
(D) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।

230. मध्य प्रदेश की राजनीति में महिलाओं का सशक्तिकरण किसके द्वारा महत्वपूर्ण रूप से आगे बढ़ा है?
(A) उन्हें मतदान करने से रोककर।
(B) स्थानीय स्वशासन में सीटों का आरक्षण, जो राजनीतिक प्रवेश के लिए एक मंच प्रदान करता है।
(C) उनकी भूमिका को घर के कामों तक सीमित करके।
(D) राज्य सचिवालय की जटिल प्रक्रियाओं द्वारा।

231. मध्य प्रदेश में राज्य सचिवालय की प्राथमिक भूमिका क्या है?
(A) जमीनी स्तर पर कार्यों का निष्पादन।
(B) नीति निर्माण, पर्यवेक्षण और नियंत्रण।
(C) सरकारी कार्यों की न्यायिक समीक्षा।
(D) राजधानी शहर में नगरपालिका सेवाओं का प्रबंधन।

232. नीतिगत मामले पर नगर निगम की निर्वाचित परिषद और राज्य द्वारा नियुक्त आयुक्त के बीच टकराव किसके मुद्दे का उदाहरण है?
(A) स्थानीय स्वशासन में वित्त और स्वायत्तता।
(B) नक्सली समस्या।
(C) मुख्य सचिव की भूमिका।
(D) जनजातीय वर्गों का सशक्तिकरण।

233. मध्य प्रदेश में विकास की राजनीति किसके दौरान सबसे अधिक दिखाई देती है?
(A) जनगणना कार्यों के दौरान।
(B) चुनावों से पहले की अवधि में, नई योजनाओं और परियोजनाओं की घोषणाओं के साथ।
(C) उच्च न्यायालय की दैनिक कार्यवाही के दौरान।
(D) लिपिकीय कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया के दौरान।

234. निम्नलिखित अभिकथन (A) और कारण (R) पर विचार कीजिए:
अभिकथन (A): मध्य प्रदेश की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी से राजनीतिक प्राथमिकताओं में बदलाव आया है।
कारण (R): महिला प्रतिनिधि, विशेष रूप से स्थानीय स्तर पर, अक्सर जल, स्वच्छता, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे मुद्दों को प्राथमिकता देती हैं, जिन्हें पहले नजरअंदाज किया गया था।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

235. मध्य प्रदेश की राजनीति के संदर्भ में 'वंचित वर्ग' शब्द में आम तौर पर कौन शामिल नहीं होता है?
(A) अनुसूचित जाति।
(B) अनुसूचित जनजाति।
(C) अन्य पिछड़ा वर्ग।
(D) आर्थिक और सामाजिक रूप से प्रभावशाली उच्च जातियां।

NODIA

(D) स्थानीय स्वशासन की स्वायत्तता में वृद्धि।

155. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:
सूची I: (अधिकारी/प्रतिनिधि)
P. महापौर
Q. सचिव
R. सरपंच
S. कलेक्टर
सूची II: (संस्था)
1. ग्राम पंचायत
2. जिला प्रशासन
3. नगर निगम
4. राज्य सचिवालय
(A) P-3, Q-4, R-1, S-2
(B) P-1, Q-2, R-3, S-4
(C) P-3, Q-1, R-4, S-2
(D) P-4, Q-3, R-2, S-1

156. मध्य प्रदेश स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में 'नौकरशाही' शब्द का अर्थ है:
(A) पंचायतों और नगर पालिकाओं के निर्वाचित अध्यक्ष।
(B) मुख्य कार्यपालन अधिकारी और मुख्य नगरपालिका अधिकारी जैसे अधिकारी जो स्थायी सरकारी सेवा का हिस्सा हैं।
(C) लालफीताशाही और देरी की प्रक्रिया।
(D) वह राजनीतिक दल जो राज्य स्तर पर सरकार बनाता है।

157. मध्य प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
(A) राज्य में एक महत्वपूर्ण जनजातीय आबादी है जिसका सशक्तिकरण एक राजनीतिक मुद्दा है।
(B) कुछ जिलों, विशेष रूप से पूर्वी भाग में, नक्सली उग्रवाद का सामना करना पड़ा है।
(C) महिलाओं ने राज्य विधानसभा में 100% प्रतिनिधित्व प्राप्त कर लिया है।
(D) विकास परियोजनाओं का आवंटन राज्य की राजनीति का एक प्रमुख पहलू है।

158. निम्नलिखित अभिकथन (A) और कारण (R) पर विचार कीजिए:
अभिकथन (A): मध्य प्रदेश में सचिवालय को राज्य स्तरीय नीति निर्माण का प्राथमिक केंद्र माना जाता है।
कारण (R): इसमें विषय-विशेषज्ञ और पेशेवर प्रशासक कार्यरत हैं जो राजनीतिक कार्यपालिका को आवश्यक डेटा, विश्लेषण और मसौदा प्रस्ताव प्रदान करते हैं।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

159. मध्य प्रदेश में एक नगर निगम की शक्तियों में आमतौर पर निम्नलिखित को छोड़कर सभी शामिल हैं:
(A) शहर की सड़कों और पार्कों का निर्माण और रखरखाव।
(B) सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता का विनियमन।
(C) जल आपूर्ति का प्रबंधन।
(D) राज्य पुलिस बल का प्रशासन।

160. "विकास की राजनीति" के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन I: "विकास की राजनीति" का तात्पर्य है कि विकास पर निर्णय किसी भी दलीय हित से मुक्त, राजनीतिक शून्य में लिए जाते हैं।
कथन II: मध्य प्रदेश में "विकास की राजनीति" में राजनीतिक अभिनेता समर्थन बनाने और राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विकास नीतियों और परियोजनाओं का उपयोग करते हैं।
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
(D) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।

161. मध्य प्रदेश की एक महिला नेता द्वारा विधानसभा में लिंग आधारित वेतन असमानता का मुद्दा उठाना किसका प्रत्यक्ष उदाहरण है?
(A) नक्सली समस्या।
(B) राजनीति में विशिष्ट सामाजिक मुद्दों को उजागर करने में महिलाओं का योगदान।
(C) जिला प्रशासन का कामकाज।
(D) शहरी स्थानीय निकायों की वित्तीय स्वायत्तता।

162. मध्य प्रदेश में जिला प्रशासन का प्रमुख कौन है और समग्र समन्वय और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है?
(A) पुलिस अधीक्षक
(B) जिला एवं सत्र न्यायाधीश
(C) कलेक्टर
(D) जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी

163. मध्य प्रदेश में 'नक्सली समस्या' का मूल मुद्दा अक्सर किसके संघर्ष के रूप में देखा जाता है?
(A) शहरी योजना और डिजाइन।
(B) नगर निगमों की स्वायत्तता।
(C) अविकसित वन और आदिवासी क्षेत्रों में संसाधनों, गरिमा और विकास।
(D) मुख्य सचिव के लिए चयन प्रक्रिया।

164. मध्य प्रदेश में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के संगठन को किसके लिए डिजाइन किया गया है?
(A) भारत की विदेश नीति को लागू करना।
(B) प्रशासन और विकास योजना को जमीनी स्तर पर लाना।
(C) बड़े महानगरीय शहरों के मामलों का प्रबंधन करना।
(D) राज्य सचिवालय के कामकाज की देखरेख करना।

Downloaded from www.pdf.tube

(B) शहरी राजनीति में महिलाओं का योगदान।
(C) कलेक्टर की भूमिका।
(D) सचिवालय की संरचना।

247. मध्य प्रदेश में कलेक्टर की अध्यक्षता वाला जिला प्रशासन किसके रूप में कार्य करता है?
(A) राज्य से अलग एक स्वतंत्र सरकार।
(B) राज्य सरकार की नीतियों के क्रियान्वयन के लिए प्राथमिक क्षेत्रीय स्तर की एजेंसी।
(C) एक विशुद्ध रूप से न्यायिक निकाय।
(D) एक राजनीतिक दल का स्थानीय कार्यालय।

248. मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्गों का सशक्तिकरण एक राजनीतिक मुद्दा है क्योंकि:
(A) इसमें शक्ति और संसाधनों का पुनर्वितरण शामिल है, जो स्वाभाविक रूप से राजनीतिक है।
(B) यह एक गैर-विवादास्पद और सार्वभौमिक रूप से सहमत विषय है।
(C) यह केवल जनसंख्या के एक बहुत छोटे, महत्वहीन हिस्से से संबंधित है।
(D) इसका चुनावी परिणामों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

249. निम्नलिखित अभिकथन (A) और कारण (R) पर विचार कीजिए:
अभिकथन (A): कलेक्टर की भूमिका जिले में सामान्य प्रशासन से लेकर संकट प्रबंधन तक फैली हुई है।
कारण (R): बाढ़, अकाल या बड़ी दुर्घटनाओं जैसी स्थितियों में, कलेक्टर सभी बचाव, राहत और पुनर्वास प्रयासों के समन्वय के लिए जिम्मेदार मुख्य प्राधिकारी होता है।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

250. मध्य प्रदेश में नक्सली समस्या का मुकाबला करने की किसी भी रणनीति की प्रभावशीलता किस पर निर्भर करती है?
(A) विकास के लिए सुरक्षा बलों और नागरिक प्रशासन के बीच सफल समन्वय पर।
(B) समस्या को पूरी तरह से नजरअंदाज करने पर।
(C) केवल शहरी बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित करने पर।
(D) अप्रभावित क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन की शक्तियों को बढ़ाने पर।

251. कौन सा कथन मध्य प्रदेश के सचिवालय और जिला प्रशासन के बीच के संबंध को सबसे सटीक रूप से परिभाषित करता है?
(A) जिला प्रशासन सचिवालय से वरिष्ठ है।
(B) सचिवालय नीतियां बनाता है और क्रियान्वयन के लिए जिला प्रशासन को निर्देशित करता है।
(C) वे दो पूरी तरह से असंबद्ध संस्थाएं हैं।
(D) जिला प्रशासन सचिवालय के क्रियान्वयन के लिए नीतियां तैयार करता है।

252. मध्य प्रदेश में जनपद पंचायत की शक्तियाँ आम तौर पर कैसी होती हैं?
(A) जिला पंचायत से अधिक व्यापक।
(B) राज्य स्तरीय विधान पर केंद्रित।
(C) दायरे में मध्यवर्ती, जो गांवों के एक ब्लॉक को कवर करती है और ग्राम पंचायतों के कार्य का समन्वय करती है।
(D) नगर निगम के समान।

253. मध्य प्रदेश में एक आदिवासी निर्वाचन क्षेत्र की एक महिला विधायक द्वारा लघु वनोपज अधिकार पर एक नए कानून की सफलतापूर्वक पैरवी करना किसके मिलन का उदाहरण है?
(A) शहरी स्थानीय सरकार और नक्सली समस्या।
(B) महिलाओं का योगदान, आदिवासियों का सशक्तिकरण और विकास की राजनीति।
(C) कलेक्टर की भूमिका और मुख्य सचिव की शक्तियां।
(D) स्थानीय सरकार में नौकरशाही और वित्तीय स्वायत्तता।

254. मध्य प्रदेश में कलेक्टर की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. कलेक्टर जिले का मुख्य राजस्व अधिकारी होता है।
2. कानून और व्यवस्था के मामलों में पुलिस पर कलेक्टर की कोई पर्यवेक्षी भूमिका नहीं होती है।
3. कलेक्टर जिला योजना समिति का अध्यक्ष होता है।
उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) केवल 1
(B) केवल 1 और 3
(C) केवल 2 और 3
(D) 1, 2 और 3

255. मध्य प्रदेश में स्थानीय स्वशासन निकायों के लिए वित्तीय स्वायत्तता की कमी अक्सर किसका कारण बनती है?
(A) उच्च स्तर का नवाचार और आत्मनिर्भरता।
(B) दीर्घकालिक परियोजनाओं की योजना बनाने में असमर्थता और राज्य द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं पर निर्भरता।
(C) नौकरशाही नियंत्रण में कमी।
(D) जमीनी स्तर के लोकतंत्र का सुदृढ़ीकरण।

256. मध्य प्रदेश में 'विकास की राजनीति' में अक्सर किसके बीच संतुलन या चुनाव शामिल होता है?
(A) दीर्घकालिक सतत विकास और अल्पकालिक लोकलुभावन उपाय।
(B) घरेलू नीति और विदेश नीति।
(C) न्यायपालिका और विधायिका की शक्तियां।
(D) मुख्य सचिव और राज्यपाल की भूमिका।

NODIA

प्रावधान किए गए हैं ताकि उन्हें शासन में अधिकार मिल सके। महिलाओं के राजनीतिक योगदान को पंचायतों में आरक्षण के माध्यम से मजबूती प्रदान की गई है। विकास की राजनीति मुख्य रूप से औद्योगिक निवेश और राज्य के बुनियादी ढांचे के विस्तार के इर्द-गिर्द घूमती है, जिससे आर्थिक प्रगति को निरंतर बढ़ावा मिलता है।

20. (D) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।
जिला कलेक्टर की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है, न कि व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री द्वारा। कलेक्टर जिला मजिस्ट्रेट के रूप में जिले की प्रशासनिक मशीनरी का प्रमुख होता है और कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है। वह जिले में शांति सुनिश्चित करने के लिए पुलिस प्रशासन के साथ समन्वय करता है। हालांकि मुख्यमंत्री का प्रशासन पर नियंत्रण होता है, लेकिन नियुक्तियां स्थापित प्रशासनिक प्रक्रिया और नियमों के माध्यम से सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा की जाती हैं।

21. (C) जिला पंचायत
मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था एक त्रि-स्तरीय ढांचे पर आधारित है, जिसके शीर्ष पर जिला पंचायत स्थित होती है। यह निकाय जिला स्तर पर ग्रामीण विकास की योजनाओं का समन्वय और पर्यवेक्षण करता है। इसके नीचे जनपद पंचायत (खंड स्तर) और सबसे आधारभूत स्तर पर ग्राम पंचायत कार्यरत होती है। जिला पंचायत राज्य सरकार और ग्राम पंचायतों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी का कार्य करती है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में शासन और विकास की प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती है।

22. (B) सरपंच - जिला पंचायत का प्रमुख
सरपंच ग्राम पंचायत का निर्वाचित प्रमुख होता है, न कि जिला पंचायत का। मध्य प्रदेश में जिला पंचायत के प्रमुख को 'अध्यक्ष' कहा जाता है। सचिवालय राज्य स्तर पर नीति निर्धारण का कार्य करता है और कलेक्टर जिला स्तर पर विभिन्न विभागों के बीच समन्वय सुनिश्चित करता है। नगर निगम के निर्वाचित प्रमुख को महापौर कहा जाता है जो शहर के नागरिक प्रशासन की देखरेख करता है। प्रशासनिक ढांचे में पदों और उनके कार्यक्षेत्रों के बीच यह स्पष्ट अंतर अत्यंत आवश्यक है।

23. (A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
मुख्य सचिव को राज्य प्रशासन की धुरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह राजनीतिक कार्यकारिणी और स्थायी नौकरशाही के बीच समन्वय का केंद्र होता है। वह मुख्यमंत्री को नीतिगत मामलों पर महत्वपूर्ण परामर्श देता है और मंत्रिमंडल की बैठकों का संचालन सुनिश्चित करता है। उसकी देखरेख में राज्य के सभी विभाग कार्य करते हैं और वह यह सुनिश्चित करता है कि शासन के विभिन्न अंगों के बीच कोई टकराव न हो। यह पद प्रशासनिक ढांचे में स्थिरता प्रदान करता है।

24. (A) सुदूर आदिवासी और वन क्षेत्रों में अलगाव और विकास की कमी।
मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में नक्सली समस्या की जड़ें सामाजिक-आर्थिक असमानता और भौगोलिक दुर्गमता में निहित हैं। सुदूर आदिवासी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क की कमी के कारण वहां के निवासी स्वयं को मुख्यधारा से अलग महसूस करते हैं। इसी अलगाव और शासन की अनुपस्थिति का लाभ चरमपंथी गुट उठाते हैं। अतः, इस समस्या के स्थाई समाधान के लिए सुरक्षा उपायों के साथ-साथ इन क्षेत्रों में समावेशी विकास पहुँचाना अत्यंत आवश्यक है।

25. (C) शहरी स्थानीय स्वशासन
भारतीय संविधान का 74वां संशोधन अधिनियम विशेष रूप से नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों जैसी शहरी स्थानीय संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा और शक्ति प्रदान करने के लिए लाया गया था। मध्य प्रदेश में इस अधिनियम ने शहरी निकायों को अधिक स्वायत्तता, निश्चित कार्यकाल और नियमित चुनाव का अधिकार दिया है। इसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में नागरिक सुविधाओं के प्रबंधन और नियोजन में स्थानीय निवासियों की भागीदारी को बढ़ाना है, जिससे शहरों का विकास अधिक व्यवस्थित हो सके।

26. (A) केवल 1
73वें और 74वें संविधान संशोधन के बाद मध्य प्रदेश में स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण अनिवार्य हो गया, जिससे उनकी राजनीतिक भागीदारी में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। महिलाएं अब केवल मतदाता नहीं हैं, बल्कि वे सरपंच, अध्यक्ष और महापौर जैसे पदों पर आसीन होकर सक्रिय रूप से शासन संचालित कर रही हैं। राज्य के विकास में महिला राजनीतिज्ञों का योगदान महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता जैसे जमीनी मुद्दों को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल किया है।

27. (D) कलेक्टर के ऊपर और वह एक संभाग का प्रभारी होता है।
मध्य प्रदेश के प्रशासनिक पदानुक्रम में आयुक्त का स्थान जिला कलेक्टर से ऊपर होता है। वह एक 'संभाग' का प्रशासनिक प्रमुख होता है, जिसके अंतर्गत कई जिले शामिल होते हैं। आयुक्त का मुख्य कार्य अपने संभाग के भीतर विभिन्न जिलों के कलेक्टरों के कार्यों का पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन करना है। वह राज्य सरकार और जिलों के बीच एक प्रभावी कड़ी के रूप में कार्य करता है, जिससे क्षेत्रीय विकास और प्रशासन में एकरूपता और बेहतर समन्वय सुनिश्चित होता है।

28. (B) विकास की राजनीति
मध्य प्रदेश में राजमार्गों, बांधों और सिंचाई नहरों जैसी बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर अत्यधिक राजनीतिक ध्यान दिया जाना 'विकास की राजनीति' का स्पष्ट प्रमाण है। राजनीतिक दल विकास कार्यों को अपनी सफलता और जनता के प्रति प्रतिबद्धता के रूप में प्रस्तुत करते हैं। ऐसी परियोजनाएं आर्थिक प्रगति का आधार बनती हैं और चुनाव के समय मतदाताओं को आकर्षित करने का प्रमुख मुद्दा होती हैं। इसमें

Click Here to Buy book on Amazon

STUDYING FROM PDFs?

THINK AGAIN.

If you are studying only from PDFs,
you are wasting valuable time.

Research shows that learning from

PRINTED BOOKS has up to

4× HIGHER RETENTION

than studying from screens.

PRINT BOOK = BETTER MEMORY

PDF = LOWER RETENTION

Those who study from **PRINTED BOOKS**
move **AHEAD.**

Others are left **BEHIND**
in competition.

In competitive exams,
being average is not enough.

STAY ONE STEP AHEAD.

268. मध्य प्रदेश सचिवालय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
(A) यह राज्य का सर्वोच्च विधायी निकाय है।
(B) यह उन मंत्रियों से बना है जो सीधे क्षेत्र में नीतियों को क्रियान्वित करते हैं।
(C) यह राज्य सरकार का प्रशासनिक मुख्यालय है, जो मंत्रियों को नीतिगत सहायता प्रदान करता है।
(D) यह एक स्वतंत्र न्यायिक निकाय है।

269. मध्य प्रदेश की राजनीति में जनजातीय वर्गों का सशक्तिकरण आंतरिक रूप से किस मुद्दे से जुड़ा हुआ है?
(A) शहरी बुनियादी ढांचा।
(B) 'जल, जंगल और जमीन' पर अधिकार।
(C) अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौते।
(D) सचिवालय का संगठन।

270. मध्य प्रदेश प्रशासन के भीतर निम्नलिखित को ऊपर से नीचे तक सही पदानुक्रमित क्रम में व्यवस्थित करें।
1. किसी विभाग का सचिव
2. मुख्य सचिव
3. अवर सचिव
4. उप सचिव

सही क्रम चुनिए:
(A) 2, 1, 4, 3
(B) 1, 2, 4, 3
(C) 2, 1, 3, 4
(D) 4, 3, 1, 2

271. जब मध्य प्रदेश के किसी जिले का कलेक्टर विभिन्न विभागों के सभी जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक बुलाता है, तो वह किस रूप में अपनी भूमिका निभा रहा होता है?
(A) न्यायाधीश
(B) विधायक
(C) समन्वयक
(D) राजनेता

272. निम्नलिखित अभिकथन (A) और कारण (R) पर विचार कीजिए:
अभिकथन (A): वित्तीय स्वायत्तता को स्थानीय स्वशासन का जीवन-रक्त माना जाता है।
कारण (R): पर्याप्त और स्वतंत्र वित्तीय संसाधनों के बिना, मध्य प्रदेश में स्थानीय निकाय अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से नहीं कर सकते या सही मायने में स्वशासित नहीं हो सकते।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

273. मध्य प्रदेश में स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में 'नौकरशाही' में कौन से अधिकारी शामिल हैं?
(A) सरपंच और वार्ड सदस्य।
(B) महापौर और पार्षद।
(C) मुख्य नगर पालिका अधिकारी और पंचायत सचिव।
(D) विधान सभा के सदस्य।

274. मध्य प्रदेश विधान सभा में बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए विशेष आर्थिक पैकेज प्रदान करने पर बहस किसका प्रत्यक्ष उदाहरण है?
(A) महिलाओं का सशक्तिकरण।
(B) क्षेत्रीय विकास की राजनीति।
(C) शहरी स्थानीय सरकार का संगठन।
(D) मुख्य सचिव की भूमिका।

275. मध्य प्रदेश में किस निकाय के पास ग्राम पंचायत के वार्षिक बजट और विकास योजनाओं को मंजूरी देने की शक्ति है?
(A) उच्च न्यायालय
(B) राज्य सचिवालय
(C) ग्राम सभा
(D) प्रधानमंत्री कार्यालय

276. मध्य प्रदेश में प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. एक आयुक्त का अधिकार क्षेत्र कई जिलों तक फैला होता है।
2. एक सचिव आमतौर पर राज्य स्तर पर एक एकल सरकारी विभाग का प्रभारी होता है।
3. मुख्य सचिव प्रशासनिक रूप से आयुक्तों और सचिवों दोनों से वरिष्ठ होता है।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2 और 3
(C) केवल 3
(D) 1, 2 और 3

277. जिले में सरकार की 'आंख और कान' के रूप में कलेक्टर की भूमिका का अर्थ है कि उससे क्या अपेक्षा की जाती है?
(A) नागरिकों के निजी जीवन की जासूसी करना।
(B) राज्य सरकार को सभी महत्वपूर्ण घटनाक्रमों और जिले की सामान्य स्थिति के बारे में सूचित रखना।
(C) केवल समस्याओं को सुनना लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं करना।
(D) केवल समस्याओं को देखना लेकिन उनकी रिपोर्ट नहीं करना।

278. मध्य प्रदेश में नक्सली समस्या को संबोधित करने में मुख्य राजनीतिक चुनौतियों में से एक है:
(A) मानवाधिकारों की सुरक्षा और विकास पर ध्यान देने के साथ एक मजबूत सुरक्षा प्रतिक्रिया की आवश्यकता के बीच संतुलन बनाना।
(B) नए शहरी केंद्र बनाने की उच्च लागत।
(C) राजनीति में महिलाओं की कमी।

Downloaded from www.pdf.tube

257. निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश की ग्रामीण स्थानीय स्वशासन संरचना में एक स्तर नहीं है?
(A) ग्राम पंचायत
(B) नगर निगम
(C) जनपद पंचायत
(D) जिला पंचायत

258. निम्नलिखित अभिकथन (A) और कारण (R) पर विचार कीजिए:
अभिकथन (A): मध्य प्रदेश में नौकरशाही को अक्सर स्थानीय स्वशासन की स्वायत्तता में बाधा के रूप में देखा जाता है।
कारण (R): राज्य द्वारा प्रतिनियुक्त अधिकारी निर्वाचित स्थानीय निकाय की तुलना में राज्य प्रशासनिक पदानुक्रम के प्रति अधिक वफादार हो सकते हैं, जिससे हितों और प्राथमिकताओं का टकराव होता है।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

259. मध्य प्रदेश में वंचित वर्गों को सशक्त बनाने का एक प्रमुख पहलू उनकी किस तक पहुंच सुनिश्चित करना है?
(A) आर्थिक विकास के बिना केवल राजनीतिक शक्ति।
(B) शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आर्थिक अवसर।
(C) एक अलग कानूनी प्रणाली।
(D) केवल राज्य सचिवालय के भीतर पद।

260. मध्य प्रदेश सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है?
(A) मुख्यमंत्री
(B) गृह मंत्री
(C) मुख्य सचिव
(D) भोपाल के आयुक्त

261. मध्य प्रदेश की राजनीति में महिलाओं के योगदान को सबसे स्पष्ट रूप से किसके माध्यम से संस्थागत बनाया गया है?
(A) राज्यपाल का कार्यालय।
(B) पंचायत और नगरपालिका चुनावों में सीटों का आरक्षण।
(C) राज्य सिविल सेवा परीक्षा।
(D) राज्य पुलिस की संरचना।

262. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:
सूची I: (कार्य)
P. जिले में भूमि अभिलेखों का रखरखाव
Q. राज्य शिक्षा नीति का निर्धारण
R. गांव में स्वच्छता का प्रावधान
S. कई जिलों का पर्यवेक्षण
सूची II: (प्राथमिक जिम्मेदार अधिकारी/निकाय)
1. सचिव, शिक्षा विभाग
2. कलेक्टर
3. आयुक्त
4. ग्राम पंचायत
(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-2, Q-1, R-4, S-3
(C) P-2, Q-3, R-4, S-1
(D) P-4, Q-1, R-2, S-3

263. जिला मजिस्ट्रेट के रूप में कलेक्टर की भूमिका उसे कौन सी शक्ति देती है?
(A) सार्वजनिक व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए आदेश जारी करना।
(B) राज्य का बजट पारित करना।
(C) अन्य कलेक्टरों की नियुक्ति करना।
(D) भारतीय दंड संहिता में संशोधन करना।

264. "नक्सली समस्या" के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन I: मध्य प्रदेश में "नक्सली समस्या" एक शब्द है जिसका उपयोग इंदौर में यातायात की भीड़ का वर्णन करने के लिए किया जाता है।
कथन II: "नक्सली समस्या" राज्य के कुछ सुदूर और अविकसित हिस्सों में वामपंथी चरमपंथी उग्रवाद को संदर्भित करती है।
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
(D) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।

265. मध्य प्रदेश में शहरी और ग्रामीण स्थानीय स्वशासन का अस्तित्व किस सिद्धांत पर आधारित है?
(A) तानाशाही
(B) केंद्रीकृत योजना
(C) लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण
(D) राजतंत्रीय शासन

266. मध्य प्रदेश में एक विशिष्ट क्षेत्र को सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र के रूप में विकसित करने का चुनावी अभियान किसका स्पष्ट उदाहरण है?
(A) विकास की राजनीति।
(B) नक्सली मुद्दा।
(C) मुख्य सचिव की भूमिका।
(D) स्थानीय निकायों की स्वायत्तता।

267. मध्य प्रदेश में एक महिला सरपंच की सफलता अक्सर किस पर निर्भर करती है?
(A) सामाजिक बाधाओं को दूर करने और अपने आधिकारिक अधिकारों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की उसकी क्षमता पर।
(B) राज्य की राजधानी से उसकी दूरी पर।
(C) उसके परिवार में पुरुषों की संख्या पर।
(D) उसकी शिक्षा की कमी पर।

NODIA

(D) न्यायिक मामलों में अनुभव।

290. मध्य प्रदेश में विकास की राजनीति को किसमें शामिल होने के लिए शहरों के बीच की प्रतिस्पर्धा में देखा जा सकता है?
(A) राज्य मंत्रिमंडल।
(B) नक्सल प्रभावित सूची।
(C) स्मार्ट सिटी मिशन।
(D) राज्य की छुट्टियों की सूची।

291. मध्य प्रदेश के प्रशासनिक ढांचे में आयुक्त का प्राथमिक कार्य क्या है?
(A) किसी गांव का सीधे प्रशासन करना।
(B) राज्य सचिवालय और उसके संभाग के भीतर के जिला प्रशासनों के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करना।
(C) राज्य पुलिस के प्रमुख के रूप में कार्य करना।
(D) राज्य विधान सभा की अध्यक्षता करना।

292. मध्य प्रदेश की राजनीति में वंचित वर्गों के सशक्तिकरण का उद्देश्य किसे सुधारना है?
(A) राज्य का राजकोषीय घाटा।
(B) ऐतिहासिक अन्याय और संरचनात्मक असमानताएँ।
(C) हाल के खेल आयोजनों के परिणाम।
(D) सचिवालय की प्रशासनिक संरचना।

293. मध्य प्रदेश में स्थानीय स्वशासन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. इसका प्रभावी कामकाज वित्त, नौकरशाही और स्वायत्तता पर बहुत अधिक निर्भर करता है।
2. यह पूरी तरह से असफल रहा है और इसका कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकला है।
3. इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त है।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(A) केवल 1 और 3
(B) केवल 2
(C) केवल 2 और 3
(D) 1, 2 और 3

294. जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में जिले में चुनाव कराने की कलेक्टर की जिम्मेदारी इस भूमिका के किस महत्व को रेखांकित करती है?
(A) राजनीतिक प्रकृति।
(B) लोकतांत्रिक प्रक्रिया में महत्व।
(C) न्यायिक चरित्र।
(D) महत्व की कमी।

295. मध्य प्रदेश में शहरी स्थानीय स्वशासन का संगठन और शक्तियां मुख्य रूप से किससे प्राप्त होती हैं?
(A) 74वां संविधान संशोधन अधिनियम और संबंधित राज्य नगरपालिका कानून।
(B) ब्रिटिश संसदीय आदेश।
(C) स्थानीय ग्राम पंचायतों के निर्णय।
(D) मुख्य सचिव का कार्यालय।

296. मध्य प्रदेश में नक्सली समस्या से संबंधित राजनीतिक परिदृश्य में किसके बारे में बहस शामिल है?
(A) स्कूल गणवेश का रंग।
(B) विशुद्ध सुरक्षा-आधारित समाधान बनाम सामाजिक-आर्थिक समाधान की प्रभावकारिता।
(C) भोपाल के महापौर का चुनाव।
(D) मुख्य सचिव का वेतन।

297. मध्य प्रदेश की राजनीति में महिलाओं के योगदान को किसके द्वारा महत्वपूर्ण बढ़ावा मिला है?
(A) चुनावी प्रक्रिया से उनके बहिष्कार द्वारा।
(B) 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा।
(C) सचिवालय में सत्ता के केंद्रीकरण द्वारा।
(D) ग्राम पंचायतों के उन्मूलन द्वारा।

298. निम्नलिखित अभिकथन (A) और कारण (R) पर विचार कीजिए:
अभिकथन (A): राज्य सचिवालय मध्य प्रदेश का सर्वोच्च नीति निर्धारक निकाय है।
कारण (R): सचिवालय का प्रत्येक सचिव सीधे जनता द्वारा चुना जाता है।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

299. मध्य प्रदेश में "विकास की राजनीति" अनिवार्य रूप से वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा:
(A) राजनीतिक कार्रवाई और निर्णय लेने के माध्यम से विकास लक्ष्यों का अनुसरण किया जाता है।
(B) विकास से सारी राजनीति हटा दी जाती है।
(C) राजनीतिक गतिविधि द्वारा विकास को रोक दिया जाता है।
(D) केवल राजनेताओं को ही विकास का लाभ मिलता है।

300. मध्य प्रदेश में ग्रामीण और शहरी स्थानीय स्वशासन संरचनाओं को बनाने का अंतिम उद्देश्य क्या है?
(A) जिला कलेक्टर और संभागीय कार्यालयों के प्रशासनिक कार्यभार को बढ़ाना।
(B) स्थानीय स्तर पर राज्य सरकार के प्राधिकार और पहुंच को महत्वपूर्ण रूप से कमजोर करना।
(C) जमीनी स्तर के लोकतंत्र को मजबूत करना और शासन में प्रभावी स्थानीय भागीदारी को सक्षम बनाना।
(D) सेवानिवृत्त वरिष्ठ लोक सेवकों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करना।

www.nodia.in

Click Here to Buy book on Amazon

उत्तर (व्याख्या सहित)

NODIA

1. (B) नीति निर्माण और निगरानी के लिए राज्य सरकार का मुख्य प्रशासनिक कार्यालय।
मध्य प्रदेश में सचिवालय राज्य प्रशासन का सर्वोच्च निकाय है, जो मुख्य सचिव के कुशल नेतृत्व में संचालित होता है। यह शासन की महत्वपूर्ण नीतियों के निर्माण में मंत्रियों को विशेषज्ञ सहायता और आवश्यक परामर्श प्रदान करता है। विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करना और सरकारी कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन की निरंतर निगरानी करना इसकी मुख्य जिम्मेदारी है। यह राज्य सरकार के तंत्रिका केंद्र के रूप में कार्य करता है।

2. (A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
स्थानीय स्वशासन का मूल उद्देश्य सत्ता का लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करना है ताकि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के नागरिक शासन की प्रक्रिया में सीधे सहभागी बन सकें। जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए यह आवश्यक है कि इन निकायों के पास पर्याप्त वित्तीय स्वायत्तता हो। धन की कमी या राज्य पर अत्यधिक निर्भरता उनके प्रभावी कामकाज और स्थानीय विकास की योजनाओं के क्रियान्वयन में बड़ी बाधा उत्पन्न करती है।

3. (C) मुख्य सचिव
मध्य प्रदेश में मुख्य सचिव को राज्य की प्रशासनिक मशीनरी का सर्वोच्च अधिकारी माना जाता है। वह राज्य सचिवालय का प्रमुख होता है और मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार के रूप में कार्य करता है। राज्य के संपूर्ण नागरिक सेवा पदानुक्रम में उनका स्थान सबसे ऊपर होता है। वे विभिन्न सरकारी विभागों के बीच सामंजस्य बिठाने, अंतर-विभागीय विवादों को सुलझाने और कैबिनेट के निर्णयों को जमीनी स्तर पर लागू करने हेतु उत्तरदायी होते हैं।

4. (A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
मध्य प्रदेश में जिला प्रशासन की धुरी जिला कलेक्टर होता है, जो प्रशासनिक व्यवस्था में बहुआयामी भूमिका निभाता है। राजस्व संग्रहण का मुख्य अधिकारी होने के साथ-साथ वह जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य करता है। जिले की सभी विकास गतिविधियों का समन्वय करना और सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाना उसकी जिम्मेदारी है, जो उसे प्रशासन में महत्वपूर्ण बनाती है।

5. (C) स्थानीय निकायों में नौकरशाही पूरी तरह से राज्य प्रशासनिक सेवाओं से स्वतंत्र होती है।
स्थानीय स्वशासन निकायों में कार्यरत नौकरशाही पूरी तरह स्वतंत्र नहीं होती है, बल्कि यह राज्य प्रशासनिक सेवाओं का ही एक अभिन्न अंग है। राज्य सरकार अक्सर अपने अनुभवी अधिकारियों को इन निकायों में महत्वपूर्ण पदों पर प्रतिनियुक्त करती है। ये अधिकारी निर्वाचित प्रतिनिधियों को आवश्यक तकनीकी और प्रशासनिक सहायता प्रदान करते हैं। कभी-कभी नीतियों के क्रियान्वयन को लेकर निर्वाचित सदस्यों और इन अधिकारियों के बीच प्रशासनिक दृष्टिकोण में भिन्नता के कारण संघर्ष भी होता है।

6. (B) शहरी स्थानीय स्तर पर विकास की राजनीति।
नगर निगम द्वारा कचरा प्रबंधन और डिजिटल सेवाओं जैसी आधुनिक सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित करना विकास की राजनीति को दर्शाता है। शहरी क्षेत्रों में आधुनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण और 'स्मार्ट सिटी' जैसी पहल राजनीतिक दलों के लिए अपनी कार्यक्षमता प्रदर्शित करने का एक माध्यम होती हैं। ऐसी परियोजनाएं न केवल नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार करती हैं, बल्कि शहरी मतदाताओं के बीच राजनीतिक समर्थन को मजबूत करने में भी भूमिका निभाती हैं।

7. (A) P-3, Q-1, R-4, S-2
मुख्य सचिव राज्य नौकरशाही का सर्वोच्च पद है जो पूरे प्रशासन का समन्वय करता है। कलेक्टर जिले की प्रशासनिक इकाई का प्रमुख होता है और जिला स्तरीय शासन संभालता है। आयुक्त मुख्य रूप से नगर निगमों के कामकाज और शहरी विकास की देखरेख के लिए जिम्मेदार होता है। गृह विभाग का सचिव राज्य स्तर पर कानून और व्यवस्था से संबंधित नीतियों का निर्माण करता है। ये सभी पद राज्य प्रशासन के सुचारु संचालन में अत्यंत महत्वपूर्ण और निर्णायक होते हैं।

8. (A) लक्षित शैक्षिक और आर्थिक उत्थान कार्यक्रमों को लागू करना।
मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के सशक्तिकरण हेतु सबसे प्रभावी प्रारंभिक कदम उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। इसके लिए शिक्षा तक सुलभ पहुंच और रोजगार के अवसरों का सृजन अत्यंत आवश्यक है। लक्षित कार्यक्रमों के माध्यम से कौशल विकास और वित्तीय सहायता प्रदान करना उन्हें मुख्यधारा में शामिल करने में मदद करता है। बिना आर्थिक और शैक्षिक उत्थान के केवल राजनीतिक प्रतिनिधित्व से समग्र सशक्तिकरण का लक्ष्य प्राप्त नहीं होता।

9. (C) सभी विधायी कार्यवाही और पार्टी नेतृत्व की भूमिकाओं पर विशेष रूप से हावी होना।
मध्य प्रदेश की राजनीति में महिलाओं का योगदान निरंतर बढ़ रहा है, लेकिन वे अभी भी विधायी कार्यवाही और पार्टी नेतृत्व के सभी क्षेत्रों पर पूर्णतः हावी नहीं हैं। हालांकि, उन्होंने कैबिनेट में महत्वपूर्ण पद संभाले हैं और स्थानीय निकायों में आरक्षण के कारण उनकी सक्रिय भागीदारी बढ़ी है। महिलाओं ने सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों का नेतृत्व भी किया

है। उनकी भूमिका सशक्तिकरण के मार्ग पर अग्रसर है, फिर भी पितृसत्तात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

10. (A) केवल 1 और 2
मध्य प्रदेश में ग्रामीण स्थानीय निकायों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने हेतु कुछ कर और शुल्क लगाने की शक्ति प्रदान की गई है। ये निकाय केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा प्रायोजित विभिन्न विकास योजनाओं और कल्याणकारी कार्यक्रमों को जमीनी स्तर पर क्रियान्वित करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। हालांकि, पंचायतों के पास उच्च न्यायालय जैसी न्यायिक शक्तियां नहीं होती हैं, क्योंकि राज्य में न्यायपालिका की संरचना स्थानीय शासन की प्रशासनिक व्यवस्था से पूरी तरह स्वतंत्र कार्य करती है।

11. (D) राज्य सरकार के अनुदानों पर अधिक निर्भरता, जिससे संभावित रूप से स्थानीय प्राथमिकताओं से समझौता हो सकता है।
शहरी स्थानीय निकायों के पास अपने स्वयं के राजस्व स्रोतों की कमी होने पर उनकी वित्तीय स्वायत्तता अत्यंत सीमित हो जाती है। इससे वे आवश्यक नागरिक सुविधाओं और विकास कार्यों के लिए राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले अनुदानों पर निर्भर हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में, स्थानीय निकायों को राज्य सरकार की प्राथमिकताओं और शर्तों के अनुसार कार्य करना पड़ता है, जिससे स्थानीय नागरिकों की विशिष्ट आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं की अनदेखी होने की संभावना बनी रहती है।

12. (B) आयुक्त - एक संभाग (कई जिलों) के प्रमुख
मध्य प्रदेश के प्रशासनिक ढांचे में आयुक्त का पद अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो एक संभाग का प्रमुख होता है। एक संभाग के अंतर्गत कई जिले आते हैं और आयुक्त इन सभी जिलों के कलेक्टरों के कार्यों की निगरानी और समन्वय करता है। वह राज्य सरकार और जिला प्रशासन के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है। मुख्य सचिव प्रशासन का प्रमुख होता है, जबकि कलेक्टर जिले की इकाई का मुख्य प्रशासनिक और कार्यकारी अधिकारी होता है।

13. (A) 1, 3, 2, 4
मध्य प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था में पदानुक्रम की दृष्टि से सचिवालय सर्वोच्च स्थान पर है जहाँ राज्य स्तरीय नीतियां बनती हैं। इसके बाद संभाग स्तर पर आयुक्त का कार्यालय आता है जो कई जिलों की निगरानी करता है। इसके पश्चात जिला प्रशासन आता है जिसका प्रमुख कलेक्टर होता है। तहसील कार्यालय पदानुक्रम में सबसे नीचे आता है जो सीधे जमीनी स्तर पर राजस्व और प्रशासनिक कार्यों का संचालन करता है। यह प्रशासनिक शक्ति के वितरण को स्पष्ट करता है।

14. (D) स्थानीय स्वशासन में वित्त और नौकरशाही की भूमिका।
निर्वाचित प्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी के बीच असहमति स्थानीय शासन में समन्वय की चुनौती को दर्शाती है। विकास योजनाओं के लिए प्राप्त धन का आवंटन कहाँ और कैसे किया जाए, इस पर अक्सर राजनीतिक प्राथमिकताओं और प्रशासनिक नियमों के बीच संघर्ष होता है। यह स्थिति स्पष्ट करती है कि स्थानीय स्वशासन की सफलता केवल वित्त पर नहीं, बल्कि नौकरशाही और निर्वाचित सदस्यों के बीच बेहतर सामंजस्य और स्पष्ट कार्य विभाजन पर भी निर्भर करती है।

15. (A) सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के मुद्दे वंचित वर्गों के लिए राजनीतिक विमर्श के केंद्र में हैं।
मध्य प्रदेश में वंचित वर्गों की राजनीतिक भागीदारी उनके सामाजिक और आर्थिक उत्थान से गहराई से जुड़ी हुई है। शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधनों तक पहुंच सुनिश्चित करना राजनीतिक विमर्श के प्रमुख विषय रहे हैं। सरकार की विभिन्न नीतियां इन समूहों के सशक्तिकरण पर केंद्रित हैं, क्योंकि वे राज्य की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा हैं। हालांकि पर्याप्त प्रगति हुई है, फिर भी वंचना के सभी मुद्दों का पूर्ण समाधान अभी भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।

16. (A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
स्थानीय स्वशासन निकायों की प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि उनके पास अपने निर्णयों को लागू करने के लिए स्वतंत्र वित्तीय संसाधन उपलब्ध हैं या नहीं। बिना वित्तीय स्वतंत्रता के, ये निकाय अपनी विशिष्ट स्थानीय समस्याओं को हल करने में सक्षम नहीं होते और उन्हें हर छोटी जरूरत के लिए राज्य सरकार पर निर्भर रहना पड़ता है। यह निर्भरता विकेंद्रीकरण की मूल भावना को कमजोर करती है, इसलिए स्वायत्तता और वित्तीय स्वतंत्रता अनिवार्य तत्व हैं।

17. (B) संसाधनों, निर्णय लेने की प्रक्रिया और राजनीतिक भागीदारी तक महिलाओं की पहुंच बढ़ाना।
महिलाओं का सशक्तिकरण केवल एक सामाजिक सुधार नहीं है, बल्कि यह उन्हें निर्णय लेने की मुख्यधारा में शामिल करने की एक व्यापक प्रक्रिया है। मध्य प्रदेश में इसका अर्थ है कि महिलाओं को न केवल मतदान का अधिकार मिले, बल्कि वे राजनीतिक पदों पर आसीन होकर नीतियों को प्रभावित कर सकें। संसाधनों पर उनका नियंत्रण और प्रशासन में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य है ताकि समाज में लैंगिक समानता और न्याय स्थापित हो सके।

18. (A) बुनियादी ढांचे, सामाजिक कल्याण और आर्थिक विकास के लिए राज्य संसाधनों के आवंटन की प्रक्रिया।
विकास की राजनीति का मुख्य केंद्र राज्य के संसाधनों का उचित और प्रभावी वितरण है। इसमें सड़कों, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी क्षेत्रों में निवेश के माध्यम से जनता का जीवन स्तर सुधारने का प्रयास किया जाता है। राजनीतिक दल विकास परियोजनाओं को अपनी उपलब्धियों के रूप में प्रस्तुत करते हैं ताकि मतदाताओं का समर्थन प्राप्त किया जा सके। इस प्रक्रिया में अक्सर विभिन्न क्षेत्रों के बीच संसाधनों के आवंटन को लेकर प्रतिस्पर्धा और राजनीतिक बहस होती है।

19. (A) P-3, Q-4, R-1, S-2
नक्सली समस्या मध्य प्रदेश के विशिष्ट जिलों में एक गंभीर सुरक्षा और सामाजिक-आर्थिक चुनौती है। आदिवासियों के सशक्तिकरण के लिए पेसा अधिनियम जैसे विशेष कानूनी

Downloaded from www.pdf.tube

38. (B) निर्वाचित प्रतिनिधि और प्रतिनियुक्त सरकारी अधिकारी।
जनपद पंचायत जैसे स्थानीय निकायों की सफलता के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच सहयोग अनिवार्य है। निर्वाचित सदस्य जनता की आवश्यकताओं और स्थानीय मुद्दों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि सरकारी अधिकारी उन योजनाओं को तकनीकी और कानूनी रूप से लागू करने की विशेषज्ञता रखते हैं। यदि इन दोनों पक्षों के बीच समन्वय की कमी होती है, तो विकास कार्यों में अनावश्यक देरी होती है और शासन की प्रभावशीलता कम हो जाती है, जिससे नागरिक असंतोष बढ़ता है।

39. (A) केवल 2
जिला प्रशासन में कलेक्टर प्रमुख होता है, लेकिन पुलिस अधीक्षक पुलिस विभाग के प्रमुख के रूप में कानून और व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होता है। वह सुरक्षा संबंधी मामलों में जिला मजिस्ट्रेट के साथ समन्वय करता है। जिले में कई अन्य स्वतंत्र विभाग भी कार्य करते हैं। विकास योजनाओं का निर्माण और वित्तपोषण केवल जिला स्तर पर नहीं होता, बल्कि ये मुख्य रूप से राज्य और केंद्र सरकारों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, जिन्हें जिला प्रशासन केवल क्रियान्वित करने की भूमिका निभाता है।

40. (A) महिलाओं का सशक्तिकरण और राज्य की विकास राजनीति का हिस्सा।
महिला और बाल विकास के लिए बजट बढ़ाना केवल वित्तीय निर्णय नहीं है, बल्कि यह राज्य की विकासोन्मुख राजनीति और सशक्तिकरण की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ऐसी नीतियों का उद्देश्य आधी आबादी की सामाजिक स्थिति में सुधार करना और उन्हें बेहतर पोषण, शिक्षा एवं सुरक्षा प्रदान करना है। यह निवेश दीर्घकालिक मानव विकास के लिए महत्वपूर्ण है और राजनीतिक दलों के लिए एक बड़े मतदाता वर्ग के कल्याण के प्रति उनकी जवाबदेही और प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है।

41. (C) मुख्य सचिव का पद पांच वर्ष की निश्चित अवधि के लिए एक कार्यकाल पद है।
मध्य प्रदेश में मुख्य सचिव का पद कोई निश्चित कार्यकाल वाला पद नहीं है। हालांकि उनकी नियुक्ति वरिष्ठता और अनुभव के आधार पर मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है, लेकिन वे मुख्यमंत्री के विश्वास और सेवानिवृत्ति की आयु तक पद पर बने रहते हैं। वे राज्य की सिविल सेवाओं के प्रमुख और कैबिनेट के सचिव के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनका स्थानांतरण या पदमुक्ति सरकार के प्रशासनिक निर्णयों पर निर्भर करती है, न कि किसी पूर्व-निर्धारित संवैधानिक समय सीमा पर।

42. (A) जाति, वर्ग और सामाजिक स्थिति।
मध्य प्रदेश के राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य में 'वंचित वर्ग' का तात्पर्य उन समुदायों से है जिन्हें ऐतिहासिक रूप से समाज की मुख्यधारा से दूर रखा गया है। यह वंचना मुख्य रूप से जाति आधारित भेदभाव, आर्थिक विपन्नता और निम्न सामाजिक स्थिति के कारण उत्पन्न हुई है। इन वर्गों को समान अवसर प्रदान करने और जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए सरकार विशेष आरक्षण और कल्याणकारी योजनाएं संचालित करती है ताकि सामाजिक न्याय और समानता के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

43. (A) P-4, Q-3, R-2, S-1
राज्य सचिवालय पूरे प्रदेश के लिए उच्च स्तरीय नीति निर्माण और विभागों के बीच समन्वय का कार्य करता है। जिला पंचायत ग्रामीण क्षेत्रों में विकास योजनाओं के क्रियान्वयन और निगरानी की देखरेख करती है। नगर निगम बड़े शहरों में सड़क, पानी और सफाई जैसी आवश्यक नागरिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। ग्राम सभा सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायत के कार्यों की समीक्षा करती है और स्थानीय विकास में ग्रामीणों की प्रत्यक्ष भागीदारी और जवाबदेही सुनिश्चित करती है।

44. (D) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।
विकास की राजनीति कभी भी राजनीतिक विचारों से पूरी तरह मुक्त नहीं होती है। वास्तव में, विकास परियोजनाओं का चयन और उनके लिए बजट का आवंटन सत्तारूढ़ दल की प्राथमिकताओं, उनकी विचारधारा और राजनीतिक लक्ष्यों पर बहुत अधिक निर्भर करता है। यद्यपि तकनीकी मूल्यांकन एक कारक है, लेकिन अंतिम निर्णय अक्सर चुनावी लाभ और राजनीतिक समर्थन को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। विकास कार्यों के माध्यम से सरकार अपनी प्रगतिशील छवि बनाने और जनता का विश्वास जीतने का निरंतर प्रयास करती है।

45. (C) विभिन्न सरकारी विभागों के बीच सामंजस्य और कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।
जिला प्रशासन में कलेक्टर की भूमिका एक कुशल समन्वयक की होती है। जिले में कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और लोक निर्माण जैसे अनेक विभाग स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, और कलेक्टर यह सुनिश्चित करता है कि ये सभी विभाग सामान्य लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मिलकर काम करें। वह विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बीच उत्पन्न होने वाले अवरोधों को दूर करता है और शासन की नीतियों को एकीकृत रूप से लागू करता है। इस समन्वय के बिना जिला स्तर पर प्रशासनिक दक्षता प्राप्त करना असंभव है।

46. (A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
73वें संविधान संशोधन ने मध्य प्रदेश में ग्रामीण शासन की संरचना को मौलिक रूप से बदल दिया। महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटों और महत्वपूर्ण पदों का आरक्षण अनिवार्य करके, इस कानून ने महिलाओं को घर की दहलीज से बाहर निकलकर शासन के सक्रिय पदों तक पहुँचाया है। यह आरक्षण न केवल उनकी संख्यात्मक भागीदारी सुनिश्चित करता है, बल्कि उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी सशक्त बनाता है, जिससे ग्रामीण विकास की प्राथमिकताओं में महिला-केंद्रित मुद्दों को अधिक महत्व मिला है।

47. (A) एक संक्रमणकालीन क्षेत्र, जो ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में विकसित हो रहा है।
नगर पंचायत मध्य प्रदेश में शहरी स्थानीय शासन की एक विशिष्ट इकाई है, जो उन क्षेत्रों के लिए गठित की जाती है जो

NODIA

संसाधनों का आवंटन अक्सर राजनीतिक प्राथमिकताओं और क्षेत्रीय विकास की मांगों से प्रेरित होता है।

29. (B) P-2, Q-1, R-4, S-3
सरपंच ग्राम पंचायत का निर्वाचित प्रमुख होता है जो ग्रामीण स्तर पर शासन संभालता है। महापौर नगर निगम का प्रमुख होता है और शहरों के नागरिक मामलों की देखरेख करता है। मुख्य सचिव राज्य सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख होता है जो पूरी राज्य मशीनरी का समन्वय करता है। जिला मजिस्ट्रेट कलेक्टर की ही एक भूमिका है जो जिले में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। ये सभी पद प्रशासन के अलग-अलग स्तरों पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का सफलतापूर्वक निर्वहन करते हैं।

30. (D) राज्य विधानसभा के सत्रों की अध्यक्षता करना।
जिला कलेक्टर के पास जिले के भीतर व्यापक प्रशासनिक और कार्यकारी शक्तियां होती हैं, जैसे राजस्व संग्रहण, कानून-व्यवस्था बनाए रखना और विकास कार्यों का समन्वय करना। हालांकि, राज्य विधानसभा के सत्रों की अध्यक्षता करना उसका कार्य नहीं है; यह जिम्मेदारी विधानसभा अध्यक्ष की होती है। कलेक्टर राज्य सरकार का एक नियुक्त अधिकारी होता है, जबकि विधानसभा एक विधायी निकाय है जिसका संचालन निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। प्रशासन और विधायिका के बीच यह कार्य विभाजन स्पष्ट है।

31. (D) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।
मध्य प्रदेश में सचिवालय एक विशुद्ध रूप से राजनीतिक निकाय नहीं है, बल्कि यह स्थायी लोक सेवकों और प्रशासनिक अधिकारियों का संस्थान है। इसका प्रशासनिक प्रमुख मुख्य सचिव होता है, जो वरिष्ठतम भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है। सचिवालय का कार्य मंत्रियों को नीति निर्माण में सहायता करना और सरकारी विभागों का प्रबंधन करना है। हालांकि यह राजनीतिक कार्यकारिणी के तहत कार्य करता है, लेकिन इसके अधिकारी पेशेवर लोक सेवक होते हैं जो शासन की निरंतरता बनाए रखते हैं।

32. (B) राज्य सरकार के अनुचित हस्तक्षेप के बिना एक परिभाषित क्षेत्र के भीतर कार्यात्मक स्वतंत्रता।
स्थानीय स्वशासन में स्वायत्तता का अर्थ है कि इन निकायों के पास अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर निर्णय लेने और विकास योजनाओं को लागू करने की पर्याप्त स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसमें वित्तीय और प्रशासनिक निर्णय शामिल हैं जो राज्य के सामान्य कानूनों के दायरे में हों। पूर्ण अलगाव संभव नहीं है, लेकिन स्वायत्तता यह सुनिश्चित करती है कि स्थानीय समस्याओं का समाधान स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार बिना किसी बाहरी राजनीतिक दबाव के प्रभावी ढंग से किया जा सके।

33. (A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
नक्सली समस्या के समाधान के लिए केवल सुरक्षा बल ही पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि उन मूल कारणों को समझना आवश्यक है जिनसे यह विचारधारा पनपती है। मध्य प्रदेश के सुदूर क्षेत्रों में गरीबी, संसाधनों का शोषण और विकास की कमी ने असंतोष को जन्म दिया है। जब शासन की पहुंच कम होती है, तो आदिवासी आबादी स्वयं को उपेक्षित महसूस करती है। अतः, इन सामाजिक-आर्थिक शिकायतों को दूर करना और समावेशी विकास सुनिश्चित करना नक्सलवाद को समाप्त करने की रणनीति का हिस्सा है।

34. (A) राजनीतिक समर्थन हासिल करने के लिए विकास परियोजनाओं हेतु कुछ क्षेत्रों या सामाजिक समूहों को प्राथमिकता देना।
विकास की राजनीति का एक प्रमुख पहलू यह है कि संसाधन और परियोजनाएं अक्सर राजनीतिक लाभ को ध्यान में रखकर आवंटित की जाती हैं। राजनीतिक दल कुछ विशेष क्षेत्रों या मतदाता समूहों को आकर्षित करने के लिए वहां बड़ी विकास योजनाओं की घोषणा करते हैं। यह प्रक्रिया दर्शाती है कि विकास केवल तकनीकी कार्य नहीं है, बल्कि यह राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और चुनावी रणनीतियों से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। इससे कभी-कभी विभिन्न क्षेत्रों के बीच विकास में क्षेत्रीय असंतुलन पैदा हो जाता है।

35. (C) सरकारी नौकरियों और शिक्षा में सकारात्मक कार्रवाई और आरक्षण की नीतियां।
पिछड़े वर्गों का सशक्तिकरण करने के लिए मध्य प्रदेश में सकारात्मक कार्रवाई एक मुख्य उपकरण रही है। इसमें शिक्षा और सरकारी सेवाओं में आरक्षण प्रदान करना शामिल है ताकि इन वर्गों को समान अवसर मिल सकें और उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके। इसके अलावा, उनके लिए विशेष छात्रवृत्तियां और आर्थिक सहायता योजनाएं भी चलाई जाती हैं। इन नीतियों का उद्देश्य ऐतिहासिक पिछड़ेपन को दूर करना और समाज के सभी वर्गों के बीच सामाजिक और आर्थिक न्याय स्थापित करना है।

36. (A) 2, 1, 3, 4
नगर निगम में किसी भी परियोजना की शुरुआत एक विभाग या समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव से होती है। इसके बाद, प्रस्ताव को परिषद के समक्ष रखा जाता है जहाँ बजट स्वीकृत किया जाता है। बजट मिलने के बाद, कार्य के लिए निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं और उपयुक्त ठेकेदार को अनुबंध दिया जाता है। अंतिम चरण में, परियोजना का भौतिक क्रियान्वयन शुरु होता है और उसकी प्रगति की निरंतर निगरानी की जाती है ताकि गुणवत्ता और समय-सीमा का पूर्ण पालन हो सके।

37. (C) एक विशिष्ट सरकारी विभाग के प्रशासन का नेतृत्व करना।
मध्य प्रदेश सचिवालय में एक सचिव की भूमिका किसी विशिष्ट विभाग के प्रशासनिक संचालन का नेतृत्व करना है। वह अपने विभाग के कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है और नीतिगत मामलों पर संबंधित मंत्री को विशेषज्ञ सलाह और प्रशासनिक डेटा प्रदान करता है। सचिव यह सुनिश्चित करता है कि सरकार के निर्णय और नियम विभाग के भीतर सही ढंग से लागू हों। वह जिले का प्रमुख नहीं होता है, बल्कि राज्य स्तर पर नीति निर्माण और विभागीय पर्यवेक्षण का मुख्य केंद्र होता है।

Click Here to Buy book on Amazon

(D) स्थानीय स्वशासन की स्वायत्तता।

279. मध्य प्रदेश में पंचायतों में आरक्षण के माध्यम से पिछड़े वर्गों का सशक्तिकरण किसका उपाय है?
(A) आर्थिक सशक्तिकरण
(B) राजनीतिक सशक्तिकरण
(C) सांस्कृतिक सशक्तिकरण
(D) न्यायिक सशक्तिकरण

280. मध्य प्रदेश में एक महिला मुख्यमंत्री किसका सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है?
(A) नौकरशाही व्यवस्था की विफलता।
(B) राज्य की राजनीति के उच्चतम स्तर पर महिलाओं का योगदान और सशक्तिकरण।
(C) स्थानीय स्वशासन की अप्रासंगिकता।
(D) नक्सली समस्या का समाधान।

281. मध्य प्रदेश में विकास की राजनीति अनिवार्य रूप से किसकी एक प्रक्रिया है?
(A) राज्य प्रायोजित विकास के संदर्भ में संसाधनों और लाभों के वितरण का निर्धारण।
(B) भारत के संविधान में संशोधन करना।
(C) उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति करना।
(D) पुलिस बल के आंतरिक प्रशासन का प्रबंधन करना।

282. मध्य प्रदेश में राज्य सचिवालय मुख्य रूप से किसके द्वारा संचालित होता है?
(A) निर्वाचित राजनेताओं द्वारा
(B) न्यायपालिका के सदस्यों द्वारा
(C) पेशेवर सिविल सेवकों द्वारा
(D) स्थानीय स्वशासन के प्रतिनिधियों द्वारा

283. मध्य प्रदेश में जिला कलेक्टर का कार्यालय किसके क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार है?
(A) संयुक्त राष्ट्र की नीतियां।
(B) जिला स्तर पर राज्य और केंद्र सरकारों की नीतियां और कार्यक्रम।
(C) एक एकल राजनीतिक दल का घोषणापत्र।
(D) केवल स्थानीय नगर निगम के निर्णय।

284. ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
कथन I: जिला पंचायत मध्य प्रदेश में जिला स्तर पर ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की शीर्ष संस्था है।
कथन II: जिला पंचायत के पास जनपद और ग्राम पंचायतों पर पर्यवेक्षी और समन्वयकारी शक्तियां हैं।
(A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
(B) कथन I और कथन II दोनों गलत हैं।
(C) कथन I सही है, लेकिन कथन II गलत है।
(D) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।

285. मध्य प्रदेश में नगर निगमों की स्वायत्तता के लिए सबसे महत्वपूर्ण चुनौती क्या है?
(A) शक्ति की अधिकता।
(B) जन भागीदारी की कमी।
(C) राज्य सरकार पर वित्तीय निर्भरता।
(D) किसी भी नौकरशाही की अनुपस्थिति।

286. निम्नलिखित अभिकथन (A) और कारण (R) पर consider कीजिए:
अभिकथन (A): मध्य प्रदेश में कलेक्टर की भूमिका बहुआयामी है।
कारण (R): कलेक्टर जिला मजिस्ट्रेट, जिला निर्वाचन अधिकारी, राजस्व प्रशासन के प्रमुख और विकास गतिविधियों के मुख्य समन्वयक के रूप में कार्य करता है।
(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
(B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।
(C) A सही है लेकिन R गलत है।
(D) A गलत है लेकिन R सही है।

287. निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश की राजनीति में महिलाओं के योगदान का प्रतिनिधित्व करता है?
(A) राज्य की साक्षरता दर में कमी।
(B) लिंग-संवेदनशील बजट और नीतियों पर ध्यान केंद्रित करना।
(C) स्थानीय स्वशासन का उन्मूलन।
(D) नौकरशाही लालफीताशाही का सुदृढ़ीकरण।

288. सूची I को सूची II से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए:
सूची I: (राजनीति का क्षेत्र)
P. स्थानीय स्वशासन
Q. नक्सली समस्या
R. राजनीति में महिलाएं
S. वंचित वर्ग
सूची II: (मुख्य मुद्दा)
1. पंचायतों में आरक्षण
2. सकारात्मक कार्रवाई नीतियां
3. स्वायत्तता बनाम नियंत्रण
4. सुरक्षा और विकास
(A) P-1, Q-2, R-3, S-4
(B) P-3, Q-4, R-1, S-2
(C) P-3, Q-1, R-4, S-2
(D) P-4, Q-3, R-2, S-1

289. मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को मुख्यमंत्री द्वारा चुना जाता है, जो किसके महत्व को दर्शाता है?
(A) केवल वरिष्ठता।
(B) राजनीतिक तटस्थता।
(C) सरकार के राजनीतिक और प्रशासनिक प्रमुखों के बीच परस्पर विश्वास।

न तो पूरी तरह ग्रामीण हैं और न ही पूर्ण विकसित शहर। ये संक्रमणकालीन क्षेत्र होते हैं जहाँ कृषि के स्थान पर गैर-कृषि गतिविधियां बढ़ रही होती हैं। नगर पंचायत का उद्देश्य इन क्षेत्रों को शहरी सुविधाएं प्रदान करना और उनके विकास को नियोजित करना है। यह ग्रामीण और शहरी प्रशासन के बीच एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक कड़ी की भूमिका निभाती है।

48. (B) स्थानीय राजनीति और विकास में महिलाओं का योगदान।
एक महिला सरपंच द्वारा लड़कियों की शिक्षा के लिए समुदाय को लामबंद करना यह दर्शाता है कि स्थानीय राजनीति में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सामाजिक सुधार का प्रभावी माध्यम है। यह उदाहरण सिद्ध करता है कि महिलाएं नेतृत्व की भूमिकाओं में शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक विकास जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर अधिक संवेदनशीलता के साथ कार्य करती हैं। आरक्षण के माध्यम से प्राप्त राजनीतिक शक्ति ने ग्रामीण समाज में महिलाओं की स्थिति को मजबूत किया है और विकास की प्राथमिकताओं को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है।

49. (B) अंतरराष्ट्रीय व्यापार टैरिफ से राजस्व
शहरी स्थानीय निकायों के वित्तीय संसाधन मुख्य रूप से स्थानीय करों और सरकारी अनुदानों तक सीमित होते हैं। संपत्ति कर, जल शुल्क और अन्य नागरिक सेवाओं के लिए वसूला जाने वाला शुल्क उनके राजस्व के प्रमुख आंतरिक स्रोत हैं। इसके अतिरिक्त, उन्हें राज्य सरकार से नियमित विकास अनुदान भी प्राप्त होते हैं। अंतरराष्ट्रीय व्यापार और उस पर लगने वाले टैरिफ केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, इसलिए यह स्थानीय निकायों के लिए वित्त का प्रत्यक्ष स्रोत नहीं हो सकता है।

50. (A) मुख्य सचिव
मध्य प्रदेश में जब सचिवालय के दो विभागों के बीच नीतिगत असहमति या विवाद उत्पन्न होता है, तो मुख्य सचिव उसे सुलझाने के लिए सर्वोच्च प्रशासनिक प्राधिकारी होता है। मुख्य सचिव राज्य की संपूर्ण प्रशासनिक मशीनरी का समन्वय करता है और अंतर-विभागीय संघर्षों को दूर कर शासन के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करता है। वह मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार के रूप में भी कार्य करता है, जिससे वह नीतिगत गतिरोधों को दूर करने और विभागों के बीच बेहतर सामंजस्य स्थापित करने में सक्षम होता है।

51. (A) केवल 2
मध्य प्रदेश में नक्सली समस्या केवल कानून और व्यवस्था का मुद्दा नहीं है, बल्कि इसके गहरे सामाजिक-आर्थिक कारण हैं। राज्य सरकार इस समस्या से निपटने के लिए दोहरी रणनीति अपनाती है: सुरक्षा बलों के माध्यम से शांति व्यवस्था बनाए रखना और उन क्षेत्रों में विकास योजनाओं को तेज करना ताकि चरमपंथी विचारधारा के प्रति आकर्षण कम हो। यह समस्या राज्य के सभी जिलों में समान रूप से नहीं है, बल्कि कुछ विशिष्ट वनांचल और सीमावर्ती जिलों तक ही सीमित है।

52. (D) अनिवार्य और विवेकाधीन कार्य
मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायतों को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए कुछ शक्तियां और जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। स्थानीय बाजारों का प्रबंधन, साफ-सफाई, सार्वजनिक स्वास्थ्य और प्राथमिक सुविधाओं का रखरखाव उनके कार्यों का हिस्सा हैं। इनमें से कुछ कार्य अनिवार्य होते हैं जिन्हें करना पंचायत के लिए आवश्यक है, जबकि कुछ अन्य कार्य संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर विवेकाधीन होते हैं। ये शक्तियां पंचायतों को स्थानीय स्तर पर आत्मनिर्भर बनाने और ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता सुधारने के उद्देश्य से दी गई हैं।

53. (C) सचिवालय राज्य प्रशासन और नीति निर्माण का तंत्रिका केंद्र है।
सचिवालय मध्य प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था का हृदय है जहाँ समस्त महत्वपूर्ण नीतियां और निर्णय लिए जाते हैं। यह मंत्रियों को प्रशासनिक डेटा और परामर्श प्रदान कर शासन चलाने में सक्षम बनाता है। मुख्य सचिव राजनीतिक प्रमुख नहीं, बल्कि प्रशासनिक प्रमुख होता है, जबकि मुख्यमंत्री राजनीतिक प्रमुख होते हैं। इसी तरह, आयुक्त कलेक्टर के ऊपर होता है न कि उसके अधीन। जिला प्रशासन राज्य सरकार की नीतियों के क्रियान्वयन का माध्यम है और वह पूरी तरह राज्य के अधीन कार्य करता है।

54. (A) 2, 4, 1, 3
राजस्व प्रशासन में पदानुक्रम की दृष्टि से राजस्व विभाग का सचिव राज्य स्तर पर सर्वोच्च नीतिगत पद है। इसके बाद संभाग स्तर पर आयुक्त आता है जो अपने क्षेत्र के जिलों की निगरानी करता है। जिला स्तर पर कलेक्टर मुख्य राजस्व अधिकारी होता है जो राजस्व संग्रहण के लिए उत्तरदायी है। तहसील स्तर पर तहसीलदार पदानुक्रम में निचला पद है जो सीधे भू-अभिलेखों और राजस्व संबंधी विवादों का प्रबंधन करता है। यह अनुक्रम राज्य में राजस्व प्रणाली के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करता है।

NODIA

55. (D) विकास की राजनीति।
नई औद्योगिक नीति के माध्यम से निवेश और रोजगार को बढ़ावा देना सीधे तौर पर 'विकास की राजनीति' का हिस्सा है। राजनीतिक दल आर्थिक प्रगति और रोजगार सृजन को अपने मुख्य एजेंडे के रूप में प्रस्तुत करते हैं ताकि जनता का विश्वास और समर्थन प्राप्त कर सकें। ऐसी नीतियां राज्य की विकास दर को बढ़ाने और मतदाताओं को अपनी कार्यकुशलता दिखाने का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक साधन होती हैं। इसमें राज्य के संसाधनों का रणनीतिक उपयोग आर्थिक लक्ष्यों और राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है।

56. (A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
स्थानीय स्वशासन में नौकरशाही और निर्वाचित प्रतिनिधियों के बीच का संबंध अत्यंत जटिल होता है। नौकरशाही के पास तकनीकी विशेषज्ञता और सरकारी नियमों का गहरा ज्ञान होता है, जो विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक है। दूसरी ओर, निर्वाचित प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं और उनके अपने राजनीतिक हित होते हैं। जब

नौकरशाही के कठोर नियम और प्रतिनिधियों की राजनीतिक प्राथमिकताएं आपस में टकराती हैं, तो प्रशासन में घर्षण उत्पन्न होता है, जो अक्सर विकास कार्यों को प्रभावित करता है।

57. (C) बुनियादी नागरिक सुविधाओं का प्रावधान और वित्तीय स्थिरता।
मध्य प्रदेश के शहरों में जनसंख्या का दबाव निरंतर बढ़ रहा है, जिससे बुनियादी सुविधाओं जैसे पानी, सफाई और सड़क की मांग में भारी वृद्धि हुई है। शहरी स्थानीय निकायों के लिए सबसे बड़ी चुनौती इन बढ़ती जरूरतों को पूरा करने और साथ ही अपने वित्तीय संसाधनों को स्थिर रखने के बीच संतुलन बनाना है। सीमित राजस्व के कारण उन्हें अक्सर राज्य सरकार की सहायता पर निर्भर रहना पड़ता है, जिससे उनकी विकास योजनाओं की गति और स्वायत्तता दोनों प्रभावित होने की संभावना बनी रहती है।

58. (A) पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम (पेसा)।
मध्य प्रदेश में जनजातीय समुदायों के सशक्तिकरण के लिए पेसा अधिनियम एक अत्यंत शक्तिशाली कानूनी उपकरण है। यह अधिनियम अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को प्राकृतिक संसाधनों और स्थानीय शासन पर व्यापक अधिकार प्रदान करता है। इसका मुख्य उद्देश्य जनजातीय संस्कृति की रक्षा करना और उन्हें अपनी विकास योजनाओं को स्वयं नियंत्रित करने की शक्ति देना है। यह संवैधानिक प्रावधान सुनिश्चित करता है कि जनजातीय वर्गों की विशिष्ट पहचान बनी रहे और वे शासन की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बन सकें।

59. (B) P-4, Q-1, R-2, S-3
मुख्य सचिव राज्य की सिविल सेवाओं का सर्वोच्च अधिकारी होता है जो पूरे प्रशासन का नेतृत्व करता है। संभाग एक प्रशासनिक इकाई है जिसमें कई जिले शामिल होते हैं और यह आयुक्त के नियंत्रण में रहता है। जिला प्रशासन की मूल इकाई है जिसका प्रमुख कलेक्टर होता है, जो जिले के समग्र विकास के लिए जिम्मेदार है। तहसील राजस्व प्रशासन के लिए जिले का एक छोटा उप-विभाजन है जहाँ तहसीलदार मुख्य प्रशासनिक कार्य करता है। यह संरचना प्रशासन को सुव्यवस्थित और प्रभावी बनाती है।

60. (B) राजनीतिक कार्यकारिणी और प्रशासनिक तंत्र के बीच मुख्य कड़ी के रूप में कार्य करना।
मुख्य सचिव का पद राज्य प्रशासन में अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि वह निर्वाचित मुख्यमंत्री और स्थायी लोक सेवा के बीच समन्वय का प्रमुख माध्यम है। वह मंत्रिमंडल के निर्णयों को विभागों के माध्यम से क्रियान्वित कराता है और प्रशासन की कार्यक्षमता की निगरानी करता है। वह राज्य के सभी सचिवों का प्रमुख होता है और जटिल प्रशासनिक समस्याओं के समाधान के लिए मुख्यमंत्री को विशेषज्ञ सलाह प्रदान करता है। इस पद के बिना राज्य सरकार की नीतियों और उनके क्रियान्वयन में सामंजस्य संभव नहीं है।

61. (D) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।
जिला कलेक्टर की एक अत्यंत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जिले में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराना है। वह जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में संसदीय और विधानसभा चुनावों की पूरी प्रक्रिया का प्रबंधन करता है, जिसमें मतदान केंद्रों की स्थापना से लेकर मतों की गिनती तक शामिल है। यह कार्य अत्यंत संवेदनशील होता है और इसमें कलेक्टर की प्रशासनिक दक्षता की परीक्षा होती है। चुनावी जिम्मेदारी कलेक्टर की कानून और व्यवस्था बनाए रखने की भूमिका के साथ भी गहराई से जुड़ी होती है।

62. (D) चरमपंथी समूहों की उपस्थिति, गतिविधि और संबंधित हिंसा।
किसी जिले को 'नक्सल प्रभावित' घोषित करने का आधार वहां चरमपंथी समूहों की सक्रियता और उनके द्वारा की जाने वाली हिंसक गतिविधियां होती हैं। राज्य सरकार इन जिलों की सुरक्षा स्थिति का निरंतर आकलन करती है और वहां खुफिया सूचनाओं के आधार पर सुरक्षा बलों की तैनाती की जाती है। इस श्रेणी में शामिल होने के बाद, उन जिलों को आंतरिक सुरक्षा और सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए विशेष बजटीय प्रावधान और अतिरिक्त सहायता प्राप्त होती है ताकि मूल समस्याओं का स्थाई समाधान किया जा सके।

63. (A) सचिव विभाग का प्रशासनिक प्रमुख होता है, जो मंत्री द्वारा निर्धारित नीतियों को लागू करने के लिए जिम्मेदार होता है।
राज्य सरकार के कामकाज में सचिव और मंत्री की भूमिकाएं एक-दूसरे की पूरक हैं। मंत्री एक निर्वाचित प्रतिनिधि होता है जो विभाग का राजनीतिक नेतृत्व करता है और नीतिगत दिशा तय करता है। सचिव एक अनुभवी लोक सेवक होता है जो विभाग का प्रशासनिक प्रमुख होता है और नीतियों के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक विशेषज्ञता और निरंतरता प्रदान करता है। यह संबंध सुनिश्चित करता है कि राजनीतिक दृष्टि को व्यावहारिक और कानूनी ढांचे के भीतर प्रभावी ढंग से जमीन पर उतारा जा सके।

64. (B) स्वच्छता, जल आपूर्ति और शिक्षा जैसे मुद्दों को स्पष्ट करना और उन्हें संबोधित करना।
मध्य प्रदेश की राजनीति में, विशेष रूप से जमीनी स्तर पर, महिलाओं की भागीदारी ने शासन की प्राथमिकताओं को बदल दिया है। निर्वाचित महिला प्रतिनिधि अक्सर उन बुनियादी मुद्दों पर अधिक ध्यान केंद्रित करती हैं जो सीधे दैनिक जीवन को प्रभावित करते हैं, जैसे स्वच्छ पेयजल, बाल शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं। उनकी सक्रियता से इन महत्वपूर्ण सामाजिक क्षेत्रों में विकास कार्यों की गति बढ़ी है। यह योगदान न केवल ग्रामीण विकास के लिए अनिवार्य है बल्कि समाज में लैंगिक संवेदनशीलता को भी बढ़ावा देता है।

65. (B) केवल 2 और 3
स्थानीय निकायों के पास अपने राजस्व के सीमित स्रोत हैं, इसलिए वे संसाधनों के लिए राज्य सरकार पर निर्भर रहते हैं। राज्य वित्त आयोग यह अनुशंसा करता है कि राज्य के कुल कर राजस्व का कितना हिस्सा पंचायतों और नगरपालिकाओं को

Downloaded from www.pdf.tube

हस्तांतरित किया जाना चाहिए। धन के हस्तांतरण में देरी या अपर्याप्त बजट इन निकायों के लिए एक बड़ी चुनौती है। पर्याप्त वित्त के बिना, ये निकाय अपनी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू नहीं कर सकते, जिससे स्थानीय शासन की कार्यात्मक स्वायत्तता प्रभावित होती है।

66. (A) राज्य सरकार को प्रशासनिक और नीति निर्माण सहायता प्रदान करना।
सचिवालय मध्य प्रदेश सरकार का मुख्य प्रशासनिक मुख्यालय है जहाँ राज्य की नीतियों का मसौदा तैयार किया जाता है। यहाँ विभिन्न विभागों के सचिव और अधिकारी मंत्रियों को डेटा, कानूनी परामर्श और तकनीकी जानकारी प्रदान करते हैं ताकि महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकें। यह विभागों के बीच समन्वय के केंद्र के रूप में कार्य करता है और यह सुनिश्चित करता है कि शासन की नीतियां पूरे राज्य में एकरूपता के साथ लागू हों। सचिवालय की कार्यकुशलता ही राज्य के प्रशासन की गुणवत्ता निर्धारित करती है।

67. (C) सामाजिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में निवेश बनाम नए बांध के निर्माण के लिए धन का आवंटन।
विकास की राजनीति में संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग को लेकर अक्सर प्रतिस्पर्धी दावे होते हैं। राजनीतिक विमर्श में यह तय करना एक बड़ी चुनौती होती है कि सीमित धन को तत्काल सामाजिक लाभ वाले कार्यक्रमों में खर्च किया जाए या दीर्घकालिक आर्थिक लाभ वाले बुनियादी ढांचे में निवेश किया जाए। ये निर्णय न केवल आर्थिक विकास को प्रभावित करते हैं, बल्कि विभिन्न समुदायों और क्षेत्रों की राजनीतिक संतुष्टि और चुनावी प्राथमिकताओं पर भी गहरा प्रभाव डालते हैं।

68. (A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
स्थानीय स्वशासन की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि स्थानीय लोग अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं करने के लिए कितने स्वतंत्र हैं। यदि इन निकायों के पास स्वायत्तता की कमी है और वे हर निर्णय के लिए राज्य सरकार के आदेशों की प्रतीक्षा करते हैं, तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। स्वायत्तता उन्हें स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप लचीली नीतियां बनाने और त्वरित निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करती है, जिससे जनता का शासन पर विश्वास बढ़ता है।

69. (C) सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए एक राजनीतिक रणनीति।
पिछड़े वर्गों के लिए कौशल विकास और वित्तीय सहायता जैसे कार्यक्रम चलाना सामाजिक न्याय प्राप्त करने की एक सोची-समझी राजनीतिक रणनीति है। ऐसी नीतियों के माध्यम से सरकार समाज के हाशिए पर स्थित समूहों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करती है। यह केवल एक प्रशासनिक कार्य नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य उन ऐतिहासिक कमियों को दूर करना है जो विकास में बाधा बनती हैं। ऐसी पहल सामाजिक समरसता बढ़ाने और समाज के सभी वर्गों का समान विकास सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

70. (B) जनपद पंचायत
मध्य प्रदेश में शहरी स्थानीय स्वशासन के तीन मुख्य स्तर हैं: नगर निगम, जो बड़े महानगरों के लिए है; नगर पालिका परिषद, जो मध्यम आकार के शहरों के लिए है; और नगर पंचायत, जो संक्रमणकालीन छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए गठित की जाती है। दूसरी ओर, जनपद पंचायत ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की एक इकाई है जो खंड स्तर पर कार्य करती है। यह वर्गीकरण जनसंख्या के घनत्व और क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों के आधार पर प्रशासनिक कुशलता सुनिश्चित करने के लिए किया गया है।

71. (D) एक ऐतिहासिक विरासत जो जिला स्तर पर प्रभावी शासन के लिए अधिकार केंद्रित करती है।
जिला कलेक्टर की दोहरी भूमिका, जिसमें वह राजस्व प्रमुख और जिला मजिस्ट्रेट दोनों होता है, भारतीय प्रशासनिक प्रणाली की एक विशिष्ट विशेषता है। यह व्यवस्था औपनिवेशिक काल से चली आ रही है और इसका उद्देश्य जिला स्तर पर प्रशासनिक अधिकारों का एकीकरण करना था ताकि कानून-व्यवस्था और सरकारी राजस्व की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। हालांकि समय के साथ इसमें विकासात्मक कार्य भी जुड़ गए हैं, लेकिन यह संरचना आज भी जिले में शासन की स्थिरता और त्वरित निर्णय लेने के लिए प्रभावी मानी जाती है।

72. (A) P-3, Q-4, R-1, S-2
राज्य सरकार का राजनीतिक नेतृत्व मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है, जो पूरी परिषद का प्रमुख होता है। जिला प्रशासन की जिम्मेदारी कलेक्टर की होती है, जो जिले का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। नगर निगम का निर्वाचित प्रमुख महापौर होता है जो शहर की नागरिक सुविधाओं का प्रबंधन करता है। ग्राम पंचायत का प्रमुख सरपंच होता है जो ग्रामीण स्तर पर विकास कार्यों और स्थानीय शासन का नेतृत्व करता है। यह संरचना शासन के विभिन्न स्तरों पर स्पष्ट जवाबदेही और कुशल नेतृत्व सुनिश्चित करती है।

73. (C) निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना और भूमि एवं वन जैसे संसाधनों पर उनके अधिकार सुरक्षित करना।
जनजातीय वर्गों के सशक्तिकरण का मूल अर्थ उन्हें आत्मनिर्भर बनाना और उनकी पारंपरिक जीवन शैली की सुरक्षा करना है। इसमें पेसा अधिनियम और वन अधिकार कानून के माध्यम से उन्हें अपने जल, जंगल और जमीन पर नियंत्रण प्रदान किया जाता है। इसके साथ ही, स्थानीय स्वशासन में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना भी एक अनिवार्य उद्देश्य है ताकि वे अपनी विकास योजनाओं को स्वयं तय कर सकें। यह प्रक्रिया उन्हें ऐतिहासिक उपेक्षा से बाहर निकालकर समाज की मुख्यधारा में सम्मानजनक स्थान दिलाती है।

74. (D) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।
मध्य प्रदेश की राजनीति में महिलाओं का योगदान हालिया नहीं है; उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम और उसके बाद के दशकों में भी सक्रिय भूमिका निभाई है। हालांकि, 73वें और 74वें संविधान संशोधनों के माध्यम से पंचायतों और नगरपालिकाओं में प्राप्त

NODIA

110. (A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
मुख्य सचिव मध्य प्रदेश के प्रशासनिक पदानुक्रम में सर्वोच्च पद है। उसकी शक्ति का मुख्य स्रोत यह है कि वह राज्य के संपूर्ण लोक सेवा तंत्र का प्रमुख होता है। मुख्यमंत्री और कैबिनेट द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णयों को व्यावहारिक रूप से लागू कराना उसी की देखरेख में होता है। वह विभागों के बीच सामंजस्य बिठाता है ताकि प्रशासनिक कार्यों में कोई गतिरोध उत्पन्न न हो। उसकी प्रभावी कार्यशैली ही यह सुनिश्चित करती है कि सरकार की कल्याणकारी योजनाएं कुशलतापूर्वक और समयबद्ध तरीके से जनता तक पहुँचें।

111. (D) राज्य का वार्षिक बजट तैयार करना।
जिला प्रशासन के पास जिले के भीतर कई महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, जैसे भू-अभिलेखों का प्रबंधन, आपदाओं के समय राहत कार्य और कानून-व्यवस्था की सुरक्षा। हालांकि, पूरे राज्य का वार्षिक बजट तैयार करना जिला प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है; यह कार्य राज्य स्तर पर वित्त विभाग और सचिवालय द्वारा किया जाता है। जिला प्रशासन केवल अपने क्षेत्र के लिए आवश्यक निधियों और खर्चों का विवरण उच्च अधिकारियों को भेज सकता है, जिसे राज्य के व्यापक बजट में शामिल करने हेतु विचार किया जाता है।

112. (A) सामाजिक न्याय और समानता प्राप्त करना।
पिछड़े वर्गों के सशक्तिकरण पर होने वाली राजनीतिक चर्चाओं का मुख्य उद्देश्य समाज में मौजूद ऐतिहासिक असमानताओं को समाप्त करना है। इसके तहत उन्हें शिक्षा और नौकरियों में उचित प्रतिनिधित्व प्रदान कर सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया जाता है। यह विमर्श केवल चुनावी लाभ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह लोकतंत्र को अधिक समावेशी बनाने का एक प्रयास है। इन वर्गों का उत्थान ही राज्य के समग्र विकास और सामाजिक समरसता के लिए अपरिहार्य माना जाता है, जिससे सभी वर्गों को प्रगति के समान अवसर मिल सकें।

113. (B) 3, 1, 2
मध्य प्रदेश में शहरी निकायों का गठन जनसंख्या और क्षेत्र की प्रकृति के आधार पर किया जाता है। नगर निगम सबसे बड़े शहरी क्षेत्रों और महानगरों के लिए होता है। नगर पालिका परिषद मध्यम आकार के शहरों के लिए गठित की जाती है। सबसे छोटा स्तर नगर पंचायत का होता है, जो गाँवों से शहरों में परिवर्तित हो रहे संक्रमणकालीन क्षेत्रों के लिए बनाया गया है। यह पदानुक्रम सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक क्षेत्र की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार प्रशासनिक ढांचा और वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जा सकें।

114. (D) जिले में न्यायपालिका के प्रमुख के रूप में कार्य करना।
जिला कलेक्टर की भूमिका अत्यंत विस्तृत है, जिसमें वह राजस्व अधिकारी, कार्यकारी मजिस्ट्रेट और विकास समन्वयक के रूप में कार्य करता है। वह चुनाव संचालन और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की निगरानी जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए भी उत्तरदायी है। हालांकि, वह जिले में न्यायपालिका का प्रमुख नहीं होता है; यह जिम्मेदारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश की होती है। भारत में कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण एक मौलिक संवैधानिक सिद्धांत है, जिसका उद्देश्य न्याय की निष्पक्षता और पूर्ण स्वतंत्रता को बनाए रखना है।

115. (A) चुनाव जीतने के लिए विकास परियोजनाओं का श्रेय लेने हेतु राजनीतिक दलों के बीच प्रतिस्पर्धा।
विकास की राजनीति में राजनीतिक दल विकास कार्यों को अपनी सफलता के रूप में जनता के सामने पेश करते हैं। मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए सड़कों, स्कूलों और अस्पतालों जैसी परियोजनाओं का उद्घाटन अक्सर चुनावों के निकट किया जाता है। राजनीतिक दल इस बात की होड़ करते हैं कि उनके शासनकाल में राज्य ने अधिक प्रगति की है। यह प्रतिस्पर्धा दर्शाती है कि विकास केवल एक प्रशासनिक कार्य नहीं है, बल्कि यह राजनीतिक अस्तित्व और सत्ता प्राप्त करने का एक अत्यंत शक्तिशाली और प्रभावी माध्यम भी है।

116. (A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
सचिवालय का संचालन वरिष्ठ लोक सेवकों द्वारा किया जाता है, जो शासन को विशेषज्ञता और निरंतरता प्रदान करते हैं। उनका मुख्य कार्य केवल फाइलों का प्रबंधन नहीं, बल्कि उच्च स्तरीय नीति निर्माण और मंत्रियों को महत्वपूर्ण विषयों पर सलाह देना है। सचिवालय स्वयं योजनाओं को जमीन पर लागू नहीं करता; यह कार्य क्षेत्रीय कार्यालयों और जिला प्रशासन का है। सचिवालय केवल नीतियों की रूपरेखा तैयार करता है, बजट आवंटित करता है और पूरे प्रदेश में उनके सुचारू क्रियान्वयन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश और आदेश जारी करता है।

117. (A) आंतरिक सुरक्षा चुनौतियां, सामाजिक-आर्थिक पिछड़ापन और शासन की कमियां।
मध्य प्रदेश में नक्सलवाद का मुद्दा केवल हथियारों की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह शासन की अनुपस्थिति और आर्थिक असमानता का परिणाम भी है। सुदूर वनांचल क्षेत्रों में विकास न पहुँचने के कारण स्थानीय लोग असंतुष्ट होते हैं, जिसका लाभ उग्रवादी तत्व उठाते हैं। अतः, इस चुनौती से निपटने के लिए एक ऐसी एकीकृत रणनीति की आवश्यकता होती है जिसमें सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के साथ-साथ गरीबी दूर करने, शिक्षा प्रदान करने और स्थानीय निवासियों को मुख्यधारा के शासन से जोड़ने के गंभीर प्रयास शामिल हों।

118. (D) इसे नौकरशाही सहायता और नियंत्रण से पूरी तरह मुक्त होने के लिए बनाया गया है।
स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है और यह लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। हालांकि, यह नौकरशाही से पूरी तरह मुक्त नहीं है। वास्तव में, पंचायतों और नगरपालिकाओं को अपने कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए राज्य द्वारा नियुक्त प्रशासनिक अधिकारियों की तकनीकी और कानूनी सहायता की आवश्यकता होती है। यह नौकरशाही सहायता कई बार नियंत्रण का रूप ले लेती है, जो स्थानीय निकायों की स्वायत्तता के लिए एक चुनौती बन जाती है। प्रशासन और निर्वाचित सदस्यों के बीच का यह जटिल संबंध ही स्थानीय शासन की धुरी है।

Click Here to Buy book on Amazon

जिले का नोडल अधिकारी होता है जो यह सुनिश्चित करता है कि विभिन्न विभागों के माध्यम से धन का सही उपयोग हो और पात्र लाभार्थियों को लाभ मिले। इस प्रकार, उसका पद विकासात्मक और जन-कल्याणकारी हो गया है।

84. (D) अक्सर राजनीतिक प्रक्रियाओं, प्राथमिकताओं और श्रेय लेने की प्रतिस्पर्धा के साथ जुड़ी होती हैं।
विकास की राजनीति का अर्थ है कि विकास कार्य केवल तकनीकी जरूरत नहीं हैं, बल्कि वे राजनीतिक विमर्श का हिस्सा होते हैं। राजनीतिक दल अक्सर इस बात की प्रतिस्पर्धा करते हैं कि कौन सी परियोजना किस क्षेत्र में आएगी और उसका श्रेय किसे मिलेगा। यह प्रक्रिया दर्शाती है कि बजट का आवंटन और परियोजनाओं का चयन अक्सर चुनावी लाभ और राजनीतिक समर्थन को ध्यान में रखकर किया जाता है। अतः, विकास और राजनीति एक-दूसरे से गहरे जुड़े हुए हैं और शासन की दिशा को प्रभावित करते हैं।

85. (C) स्थानीय स्वशासन निकायों के चुनावों का स्वतंत्र और निष्पक्ष संचालन।
मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसका मुख्य कार्य पंचायतों और नगरीय निकायों के चुनावों की देखरेख करना है। यह आयोग यह सुनिश्चित करता है कि स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र जीवंत रहे और चुनाव बिना किसी बाहरी राजनीतिक दबाव के संपन्न हों। स्वतंत्र चुनाव प्रक्रिया ही स्थानीय स्वशासन की वैधता को बनाए रखती है और जनता को अपना प्रतिनिधि चुनने का वास्तविक अधिकार प्रदान करती है। आयोग की निष्पक्षता ही ग्रामीण और शहरी स्तर पर सत्ता के विकेंद्रीकरण की नींव को मजबूत करती है।

86. (B) P-2, Q-3, R-1, S-4
जिला कलेक्टर जिला प्रशासन का मुख्य केंद्र होता है जो पूरे जिले के प्रशासनिक कार्यों का समन्वय करता है। ग्राम पंचायत ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की सबसे आधारभूत इकाई है जो गाँवों के विकास के लिए उत्तरदायी है। सचिवालय राज्य का शीर्ष प्रशासनिक निकाय है जहाँ महत्वपूर्ण नीतियां और निर्णय लिए जाते हैं। नक्सलवाद मध्य प्रदेश के कुछ विशिष्ट क्षेत्रों के लिए एक गंभीर सुरक्षा मुद्दा है। ये सभी तत्व मिलकर राज्य की जटिल और बहुआयामी शासन व्यवस्था और राजनीतिक परिदृश्य को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं।

87. (D) यह सुनिश्चित करना कि आरक्षण और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचे।
पिछड़े वर्गों के लिए बनाई गई अनेक कल्याणकारी योजनाओं की सफलता के मार्ग में सबसे बड़ी चुनौती उनका जमीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन है। अक्सर प्रशासनिक जटिलताओं और जागरूकता की कमी के कारण योजनाओं का लाभ उन लोगों तक नहीं पहुँच पाता जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। आरक्षण की नीतियों को पारदर्शी तरीके से लागू करना और यह सुनिश्चित करना कि कोई भी पात्र व्यक्ति वंचित न रहे, सशक्तिकरण की प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके लिए निरंतर निगरानी और जन-भागीदारी आवश्यक है।

88. (A) स्थानीय आर्थिक और सामाजिक विकास की योजना बनाना और नागरिक सुविधाएं प्रदान करना।
शहरी स्थानीय निकायों की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति अपने क्षेत्र के लिए विकास की रूपरेखा तैयार करना है। इसमें सड़कों का निर्माण, जल आपूर्ति का प्रबंधन, स्वच्छता बनाए रखना और शहरी गरीबों के लिए आवास जैसी नागरिक सुविधाएं प्रदान करना शामिल है। वे स्थानीय कर वसूल कर अपना राजस्व जुटा सकते हैं और अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार खर्च कर सकते हैं। यह अधिकार उन्हें स्वायत्तता प्रदान करता है ताकि वे राज्य के हस्तक्षेप के बिना अपने शहर की विशिष्ट आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से पूरा कर सकें।

89. (C) राजनीति में महिलाओं का योगदान जो सामाजिक सुधार तक फैला हुआ है।
जब कोई महिला सरपंच कन्या भ्रूण हत्या जैसी सामाजिक कुरीति के विरुद्ध खड़ा होती है, तो वह यह सिद्ध करती है कि महिला नेतृत्व केवल प्रशासनिक कार्यों तक सीमित नहीं है। उनकी उपस्थिति राजनीति में एक नैतिक और सामाजिक संवेदनशीलता लाती है। यह उदाहरण दर्शाता है कि स्थानीय निकायों में महिलाओं का सशक्तिकरण किस प्रकार समाज की रूढ़िवादी सोच को बदलने में सहायक हो सकता है। उनके ऐसे प्रयास भविष्य में एक स्वस्थ और अधिक न्यायपूर्ण समाज के निर्माण की दिशा में मील का पत्थर साबित होते हैं।

90. (D) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।
मुख्य सचिव का चयन मुख्यमंत्री द्वारा वरिष्ठ लोक सेवा अधिकारियों में से किया जाता है और वह राज्य प्रशासन के शीर्ष पर होता है। मुख्य सचिव के रूप में वह मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार और राज्य सचिवालय के प्रमुख के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि मुख्यमंत्री का उन पर नियंत्रण होता है, लेकिन उनका कार्यकाल सेवानिवृत्ति की आयु या सरकार के निर्णय पर निर्भर करता है। प्रशासनिक स्थिरता और नीतियों के क्रियान्वयन में उनका योगदान राज्य शासन के सुचारु संचालन के लिए अपरिहार्य माना जाता है।

91. (D) जिलों के एक समूह (एक संभाग) में कलेक्टरों के कार्य की निगरानी और समन्वय करना।
मध्य प्रदेश में आयुक्त का पद जिला और राज्य स्तर के बीच एक मध्यवर्ती प्रशासनिक कड़ी के रूप में कार्य करता है। एक आयुक्त के पास एक 'संभाग' का प्रभार होता है जिसमें कई जिले शामिल होते हैं। उसकी मुख्य भूमिका अपने अधीन आने वाले सभी कलेक्टरों के कार्यों का पर्यवेक्षण करना, राजस्व मामलों में अपील सुनना और क्षेत्रीय स्तर पर सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में समन्वय सुनिश्चित करना है। यह पद प्रशासन में अनुभव और नियंत्रण की एक अतिरिक्त परत जोड़ता है जो शासन को सुव्यवस्थित बनाता है।

92. (B) विशुद्ध रूप से सुरक्षा-आधारित दृष्टिकोण बनाम विकास-उन्मुख दृष्टिकोण।
मध्य प्रदेश में नक्सली समस्या से निपटने के तरीकों पर अक्सर राजनीतिक बहस होती है। एक पक्ष का मानना है कि उग्रवाद को केवल कड़े सुरक्षा उपायों और पुलिस कार्रवाई से ही समाप्त

अध्ययन करते हैं, अन्य विभागों से परामर्श करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि विधेयक संवैधानिक मानदंडों के अनुरूप हो। सचिवालय द्वारा तैयार किए गए इन्ही मसौदा प्रस्तावों को मंत्री विधान सभा में चर्चा और पारित करने के लिए प्रस्तुत करते हैं।

128. (A) उन्हें शासन और नीति निर्माण में आवाज प्रदान करना।
वंचित वर्गों के राजनीतिक सशक्तिकरण का मुख्य लक्ष्य उन्हें शक्ति संरचनाओं में समान स्थान दिलाना है। जब इन वर्गों के प्रतिनिधि पंचायत, विधान सभा या अन्य निकायों में पहुँचते हैं, तो वे अपनी विशिष्ट समस्याओं और आवश्यकताओं को सीधे शासन के समक्ष रख सकते हैं। इससे ऐसी नीतियां बनाने में मदद मिलती है जो वास्तव में उनके जीवन में सुधार ला सकें। यह प्रक्रिया उन्हें समाज का एक सक्रिय और गरिमापूर्ण हिस्सा बनाती है, जिससे लोकतंत्र अधिक समावेशी और वास्तविक अर्थों में जन-प्रतिनिधित्व वाला बन जाता है।

129. (D) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।
मध्य प्रदेश में नक्सली समस्या प्रमुख शहरों में नहीं, बल्कि उन सुदूर आदिवासी और वनांचल क्षेत्रों में है जो राज्य की सीमाओं पर स्थित हैं। ये क्षेत्र अक्सर भौगोलिक रूप से दुर्गम और आर्थिक रूप से अविकसित होते हैं, जहाँ शासन की पहुँच चुनौतीपूर्ण होती है। चरमपंथी गुट इन्ही कमियों का लाभ उठाकर अपना आधार बनाते हैं। अतः, इस समस्या की प्रकृति मुख्य रूप से ग्रामीण और वन आधारित है, जिसका समाधान उन क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करके ही प्राप्त किया जा सकता है।

130. (A) विकास की राजनीति।
विशिष्ट क्षेत्रों के लिए विकास प्राधिकरणों की स्थापना करना राज्य की नियोजित विकास रणनीति और राजनीतिक विमर्श का हिस्सा है। ये निकाय उन क्षेत्रों के बुनियादी ढांचे और शहरी सुविधाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान देते हैं। इन प्राधिकरणों के माध्यम से निवेश को आकर्षित करना और विकास की गति तेज करना सत्तारूढ़ दल की कार्यक्षमता और उनकी भविष्यवादी सोच को प्रदर्शित करता है। यह दर्शाता है कि राज्य सरकार कुछ क्षेत्रों को आर्थिक विकास के इंजन के रूप में विकसित करने की राजनीतिक प्राथमिकता रखती है ताकि समग्र प्रगति हो सके।

131. (B) जिला स्तर पर संपूर्ण सरकारी तंत्र और उसके कार्य, जो कलेक्टर के इर्द-गिर्द केंद्रित होते हैं।
जिला प्रशासन राज्य सरकार की वह इकाई है जो सीधे जनता के संपर्क में रहती है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और पुलिस जैसे सभी सरकारी विभाग शामिल होते हैं, जो जिले के भीतर अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। जिला कलेक्टर इन सभी विभागों के बीच समन्वय के मुख्य केंद्र के रूप में कार्य करता है। इसका उद्देश्य शासन की नीतियों को व्यावहारिक रूप से लागू करना, कानून-व्यवस्था बनाए रखना और स्थानीय समस्याओं का त्वरित समाधान करना है। यह प्रशासन की वह धुरी है जहाँ सरकार की प्रभावशीलता का वास्तविक अनुभव आम नागरिक को होता है।

132. (A) विधायी एजेंडे को आकार देने में राजनीति में महिलाओं का योगदान।
महिला राजनीतिक नेताओं द्वारा सामाजिक सुरक्षा और न्याय के मुद्दों को उठाना यह दर्शाता है कि उनकी उपस्थिति विधायी कार्यों में मानवीय दृष्टिकोण लाती है। घरेलू हिंसा जैसे विषयों पर कड़े कानूनों की मांग करना उनकी उन समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है जिन्हें अक्सर मुख्यधारा की राजनीति में उपेक्षित मान लिया जाता है। ऐसी पहल न केवल महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करती है, बल्कि पूरे विधायी एजेंडे को अधिक सामाजिक और न्यायपूर्ण बनाती है। यह राजनीति में महिलाओं के सक्रिय और प्रभावी नेतृत्व का एक सशक्त प्रमाण है।

133. (B) नगर निगम - एक बड़ा शहर
मध्य प्रदेश में स्थानीय निकायों का अधिकार क्षेत्र उनकी जनसंख्या और क्षेत्र के आधार पर निर्धारित है। नगर निगमों का गठन विशेष रूप से बड़े शहरों और महानगरों के प्रबंधन के लिए किया जाता है जहाँ जटिल नागरिक सुविधाएं प्रदान करने की आवश्यकता होती है। इसके विपरीत, ग्राम पंचायत केवल एक छोटे गाँव या कुछ गाँवों के समूह के लिए होती है, और जनपद पंचायत एक खंड स्तर पर कार्य करती है। जिला पंचायत का कार्यक्षेत्र पूरा जिला होता है लेकिन वह केवल ग्रामीण क्षेत्रों के विकास कार्यों का समन्वय और निगरानी करती है।

134. (A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
शहरी स्थानीय निकायों की सबसे बड़ी दुर्बलता उनकी आर्थिक पराधीनता है। यद्यपि उनके पास कुछ स्थानीय कर लगाने की शक्ति है, लेकिन प्राप्त राजस्व अक्सर बढ़ते शहरी खर्चों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त होता है। इस कारण वे अपनी बड़ी परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार के अनुदानों पर पूरी तरह निर्भर हो जाते हैं। जब ये अनुदान समय पर नहीं मिलते या उनमें कटौती की जाती है, तो सड़कों की मरम्मत और स्वच्छता जैसे अनिवार्य कार्य रुक जाते हैं। यह स्थिति स्थानीय स्वशासन की स्वायत्तता और उनकी कार्यक्षमता को गंभीर रूप से प्रभावित करती है।

135. (B) मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद
मुख्य सचिव राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है, लेकिन वह निर्वाचित सरकार के अधीन कार्य करता है। उसकी मुख्य जवाबदेही मुख्यमंत्री और राज्य मंत्रिमंडल के प्रति होती है। वह सरकार की नीतियों को प्रशासनिक रूप से अमलीजामा पहनाने और मंत्री परिषद के निर्णयों को विभागों के माध्यम से क्रियान्वित करने के लिए उत्तरदायी है। यद्यपि वह एक लोक सेवक है, लेकिन उसे शासन की राजनीतिक प्राथमिकताओं के अनुसार प्रशासनिक तंत्र का संचालन करना होता है, जिससे वह सरकार और प्रशासन के बीच की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी बन जाता है।

136. (C) प्रशासनिक, दंडाधिकारी और कार्यकारी जिम्मेदारियों का मिश्रण हैं।
मध्य प्रदेश में कलेक्टर का पद अपनी बहुआयामी प्रकृति के लिए जाना जाता है। एक ओर वह जिले का मुख्य कार्यकारी

Downloaded from www.pdf.tube

रूप में जाना जाता है। यह ग्राम पंचायत और जिला पंचायत के बीच एक सेतु की भूमिका निभाती है। जनपद पंचायत का मुख्य कार्य अपने विकास खंड के अंतर्गत आने वाली सभी ग्राम पंचायतों की योजनाओं का समन्वय करना और खंड स्तर पर विकास कार्यों की निगरानी करना है। यह स्थानीय शासन को अधिक व्यवस्थित बनाने और ग्रामीण विकास के लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए उत्तरदायी होती है।

102. (B) P-3, Q-1, R-2, S-4
आदिवासियों का सशक्तिकरण पेसा अधिनियम और वन अधिकारों की सुरक्षा के माध्यम से किया जाता है। विकास की राजनीति मुख्य रूप से राज्य में बुनियादी ढांचे और निवेश आकर्षित करने के प्रयासों पर केंद्रित रहती है। नक्सली समस्या उन विशिष्ट क्षेत्रों में अधिक है जहाँ सुरक्षा चुनौतियां और सामाजिक-आर्थिक पिछड़ापन एक साथ मौजूद हैं। शहरी स्वशासन का प्राथमिक कार्य शहरों के नागरिकों को बेहतर पानी, बिजली और सफाई जैसी सुविधाएं प्रदान करना है। ये सभी मुद्दे मध्य प्रदेश की राजनीति और शासन की आधारशिला के रूप में कार्य करते हैं।

103. (B) यह स्थानीय निकायों को स्थानीय परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार विकास योजनाएं बनाने में सक्षम बनाता है।
स्थानीय शासन में स्वायत्तता का महत्व इस तथ्य में निहित है कि स्थानीय लोग अपनी समस्याओं और जरूरतों को राज्य की राजधानी में बैठे अधिकारियों से बेहतर समझते हैं। स्वायत्तता मिलने पर, ये निकाय अपनी विशिष्ट भौगोलिक और सामाजिक स्थिति के अनुसार लचीली विकास योजनाएं तैयार कर सकते हैं। इससे सरकारी संसाधनों का अधिक प्रभावी उपयोग होता है और विकास कार्यों में जन-भागीदारी बढ़ती है। बिना स्वायत्तता के, स्थानीय निकाय केवल राज्य सरकार की योजनाओं को लागू करने वाले यांत्रिक केंद्र बनकर रह जाते हैं।

104. (A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
मध्य प्रदेश के प्रशासनिक ढांचे में कलेक्टर और आयुक्त दोनों ही अत्यंत महत्वपूर्ण कड़ियाँ हैं। कलेक्टर जिले का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है और उसे शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियां भी प्राप्त होती हैं। आयुक्त का पद कलेक्टर से ऊपर होता है और वह एक पूरे संभाग का नेतृत्व करता है, जिसमें कई जिले शामिल होते हैं। आयुक्त का मुख्य कार्य संभाग के सभी जिलों के कलेक्टरों के कार्यों का पर्यवेक्षण करना और उनके बीच बेहतर प्रशासनिक तालमेल और अनुशासन सुनिश्चित करना है।

105. (B) विकास की राजनीति।
नई औद्योगिक इकाई की स्थापना को लेकर होने वाला संघर्ष 'विकास की राजनीति' का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह विकास बनाम पर्यावरण और आजीविका की सुरक्षा के बीच के जटिल संबंधों को उजागर करता है। सरकार और उद्योग जहाँ इसे आर्थिक प्रगति के रूप में देखते हैं, वहीं स्थानीय समुदाय विस्थापन और प्रदूषण को लेकर चिंतित रहते हैं। ऐसी स्थितियों में राजनीतिक दलों को विभिन्न समूहों के प्रतिस्पर्धी हितों के बीच संतुलन बनाना पड़ता है, जिससे यह मुद्दा पूरी तरह से राजनीतिक और सामाजिक विमर्श का केंद्र बन जाता है।

106. (B) पुलिस अधीक्षक के साथ निकटता से समन्वय करना और विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देना।
नक्सल प्रभावित जिलों में कलेक्टर की जिम्मेदारी सामान्य क्षेत्रों की तुलना में कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण होती है। उसे कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल के साथ निरंतर संपर्क में रहना पड़ता है। साथ ही, चरमपंथ के मूल कारणों को दूर करने के लिए उसे सुदूर गाँवों तक शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाएं पहुँचाने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। विकास के माध्यम से जनता का विश्वास जीतना ही नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करने का सबसे प्रभावी और स्थाई प्रशासनिक तरीका माना जाता है।

107. (B) महिलाओं ने सरपंच से लेकर मुख्यमंत्री तक के पद संभाले हैं, जिससे नीति और शासन प्रभावित हुआ है।
मध्य प्रदेश के इतिहास में महिलाओं ने नेतृत्व के हर स्तर पर अपनी योग्यता सिद्ध की है। कई प्रभावी नेताओं ने मुख्यमंत्री के रूप में राज्य का नेतृत्व किया है, जबकि लाखों महिलाओं ने सरपंच बनकर ग्रामीण विकास की दिशा बदली है। उनकी भागीदारी ने शासन की प्राथमिकताओं में महिला कल्याण, स्वास्थ्य और बाल विकास जैसे मुद्दों को केंद्र में ला दिया है। यह योगदान केवल प्रतीकात्मक नहीं है, बल्कि इसने राज्य की राजनीतिक संस्कृति को अधिक संवेदनशील और समावेशी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

108. (A) केवल 1 और 2
जिला पंचायत में नौकरशाही की भूमिका निर्वाचित प्रतिनिधियों की सहायता के लिए निर्धारित है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी एक नियुक्त प्रशासनिक अधिकारी होता है जो योजनाओं को तकनीकी और कानूनी रूप से सही ढंग से लागू करने के लिए उत्तरदायी है। हालांकि, नौकरशाही का कार्य निर्वाचित सदस्यों के अधिकारों को कम करना नहीं है, बल्कि उनके लोकतांत्रिक निर्णयों को व्यावहारिक धरातल पर उतारना है। इन दोनों के बीच बेहतर तालमेल ही एक प्रभावी स्थानीय शासन की पहचान है, जो जिले में सुचारु और पारदर्शी विकास सुनिश्चित करता है।

109. (B) लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का समर्थन।
यद्यपि सचिवालय राज्य का शीर्ष प्रशासनिक केंद्र है, लेकिन इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य सत्ता को निचले स्तर तक पहुँचाने की प्रक्रिया में सहायता करना है। यह उन नीतियों और कानूनों का निर्माण करता है जो पंचायतों और नगरपालिकाओं को सशक्त बनाते हैं। सचिवालय यह सुनिश्चित करता है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के संवैधानिक प्रावधानों को राज्य भर में प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। इस प्रकार, यह केंद्र से संचालित होते हुए भी स्थानीय शासन की स्वायत्तता और उनकी कार्यक्षमता को मजबूत करने के लिए मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है।

NODIA

आरक्षण ने उनकी भागीदारी को एक नया और व्यापक आयाम दिया है। इस आरक्षण ने लाखों महिलाओं को नेतृत्व के अवसर प्रदान किए हैं, जिससे जमीनी स्तर पर शासन की शैली अधिक समावेशी और जनोन्मुखी हुई है। वे अब नीति निर्माण में प्रभावी भूमिका निभा रही हैं।

75. (A) 1, 2, 3, 4
नक्सली समस्या के समाधान के लिए एक व्यवस्थित प्रक्रिया अपनाई जाती है। सबसे पहले खुफिया जानकारी के आधार पर प्रभावित क्षेत्रों की पहचान की जाती है। इसके बाद, सुरक्षा बलों की तैनाती कर वहां कानून का शासन पुनः स्थापित किया जाता है। शांति बहाली के साथ ही, वहां के निवासियों का विश्वास जीतने के लिए सड़क, स्कूल और अस्पताल जैसी सामाजिक-आर्थिक विकास परियोजनाएं शुरू की जाती हैं। अंत में, गुमराह व्यक्तियों को मुख्यधारा में लाने के लिए आत्मसमर्पण और पुनर्वास की नीतियां लागू की जाती हैं।

76. (B) सचिव
मध्य प्रदेश सचिवालय में प्रत्येक सरकारी विभाग का प्रशासनिक संचालन सचिव द्वारा किया जाता है। सचिव एक वरिष्ठ लोक सेवक होता है जो विभाग की फाइलों, बजट और प्रशासनिक निर्णयों के लिए उत्तरदायी होता है। हालांकि विभाग का नीतिगत नेतृत्व मंत्री के पास होता है, लेकिन सचिव यह सुनिश्चित करता है कि सभी कार्य सरकारी नियमों और कानूनों के अनुसार हों। वह मंत्री को निष्पक्ष परामर्श प्रदान करता है और विभाग की प्रशासनिक कार्यक्षमता और अनुशासन को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है।

77. (C) गैर-निर्वाचित, स्थायी और पेशेवर सरकारी अधिकारी जो नीतियों को क्रियान्वित करते हैं।
स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में 'नौकरशाही' उन अधिकारियों के समूह को कहा जाता है जो प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से नियुक्त होते हैं और जिनका कार्यकाल स्थायी होता है। इनमें मुख्य कार्यपालन अधिकारी और सचिव जैसे पद शामिल हैं जो निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ मिलकर काम करते हैं। नौकरशाही का मुख्य कार्य सरकार की विकास योजनाओं को तकनीकी रूप से तैयार करना और उन्हें जमीनी स्तर पर लागू करना है। वे शासन में प्रशासनिक निरंतरता और विशेषज्ञता सुनिश्चित करने के लिए अपरिहार्य हैं।

78. (D) उच्च स्तरीय स्थानीय राजनीति में महिलाओं का सफल सशक्तिकरण और योगदान।
जिला पंचायत अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद पर महिला का निर्वाचन समाज की बदलती मानसिकता और राजनीतिक सशक्तिकरण की सफलता का परिचायक है। यह दर्शाता है कि महिलाएं अब केवल नाममात्र की भागीदारी नहीं कर रही हैं, बल्कि वे पूरे जिले के विकास की कमान संभालने में सक्षम हैं। आरक्षण ने उन्हें एक मंच प्रदान किया है जहाँ वे अपनी नेतृत्व क्षमता सिद्ध कर सकती हैं। यह उपलब्धि ग्रामीण विकास की प्राथमिकताओं में सकारात्मक बदलाव लाने और अन्य महिलाओं को प्रेरित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

79. (A) केवल 1 और 3
मध्य प्रदेश में कलेक्टर जिले का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है जो विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करता है। वह जिला मजिस्ट्रेट के रूप में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी उत्तरदायी है। हालांकि, उसके पास राज्य स्तरीय कानून बनाने की कोई शक्ति नहीं होती है, क्योंकि यह कार्य केवल राज्य विधायिका का है। कलेक्टर का पद पूरी तरह से कार्यकारी और प्रशासनिक होता है, जिसका उद्देश्य सरकार की नीतियों और कानूनों को जिला स्तर पर अक्षरशः लागू करना होता है।

80. (B) अपर्याप्त वित्त, नौकरशाही हस्तक्षेप और निर्वाचित सदस्यों की कम क्षमता।
ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के प्रभावी होने के मार्ग में कई बाधाएं हैं। इनमें सबसे प्रमुख धन की कमी है, क्योंकि वे राज्य के अनुदानों पर निर्भर रहते हैं। कई बार निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास प्रशासनिक कार्यों को समझने के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं होता, जिससे नौकरशाही का प्रभाव बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त, अधिकारियों और प्रतिनिधियों के बीच तालमेल की कमी भी विकास कार्यों की गति को धीमा कर देती है। इन चुनौतियों के कारण विकेंद्रीकरण का वास्तविक लाभ पूरी तरह ग्रामीणों तक नहीं पहुंच पाता।

81. (B) राज्य में विकास की राजनीति पूरी तरह से अस्तित्वहीन है।
मध्य प्रदेश की राजनीति में विकास एक अत्यंत महत्वपूर्ण और ज्वलंत मुद्दा है। वास्तव में, विकास की राजनीति यहाँ के चुनावी विमर्श का केंद्र है, जहाँ दल अपनी उपलब्धियों और भविष्य की परियोजनाओं के आधार पर वोट मांगते हैं। राज्य को नक्सलवाद, वंचित वर्गों के सशक्तिकरण और महिलाओं की भागीदारी जैसी कई चुनौतियों और सफलताओं का सामना करना पड़ा है। विकास की राजनीति को अस्तित्वहीन कहना पूर्णतः गलत है, क्योंकि बुनियादी ढांचे और सामाजिक कल्याण पर चर्चाएं ही राज्य की राजनीतिक दिशा तय करती हैं।

82. (A) महापौर
मध्य प्रदेश में नगर निगम शहरी स्थानीय स्वशासन का सर्वोच्च स्तर है और इसके निर्वाचित राजनीतिक प्रमुख को 'महापौर' कहा जाता है। महापौर नगर निगम की परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है और शहर के विकास संबंधी नीतिगत निर्णयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि प्रशासनिक कार्यों के लिए 'नगर निगम आयुक्त' जिम्मेदार होता है, लेकिन महापौर जनता का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होने के कारण शहर की नागरिक समस्याओं को शासन के समक्ष रखने के लिए उत्तरदायी होता है, जो लोकतांत्रिक जवाबदेही सुनिश्चित करता है।

83. (A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
आधुनिक समय में कलेक्टर की भूमिका केवल कर वसूलने तक सीमित नहीं रही है, बल्कि वह जिले के सर्वांगीण विकास का मुख्य वाहक बन गया है। सरकार की अधिकांश कल्याणकारी योजनाएं, जैसे स्वास्थ्य मिशन और ग्रामीण रोजगार योजनाएं, कलेक्टर के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में क्रियान्वित की जाती हैं। वह

Click Here to Buy book on Amazon

119. (B) राज्य स्तरीय राजनीति में महिलाओं का योगदान और भागीदारी।
राज्य सरकार में महिलाओं का मंत्री बनना यह सिद्ध करता है कि वे अब केवल मतदान तक सीमित नहीं हैं, बल्कि नीति निर्माण के उच्चतम स्तर पर सक्रिय हैं। उनकी उपस्थिति यह सुनिश्चित करती है कि शासन की योजनाओं में महिलाओं और बच्चों के हितों को पर्याप्त महत्व मिले। यह न केवल उनके व्यक्तिगत सशक्तिकरण को दर्शाता है, बल्कि पूरे समाज के लिए एक प्रेरणा के रूप में कार्य करता है। राजनीति में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी ही लोकतंत्र को अधिक परिपक्व, मानवीय और संतुलित बनाने में सहायक होती है।

120. (A) P-2, Q-4, R-1, S-3
मुख्य सचिव पूरे राज्य के प्रशासनिक तंत्र का प्रमुख होता है और सचिवालय का नेतृत्व करता है। आयुक्त एक संभाग का प्रभारी होता है और अपने क्षेत्र के कई जिलों के कार्यों का पर्यवेक्षण करता है। कलेक्टर जिला प्रशासन की धुरी होता है और जिले के सर्वांगीण विकास और कानून-व्यवस्था के लिए जिम्मेदार है। जनपद पंचायत का मुख्य कार्यपालन अधिकारी खंड स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन को देखता है। यह ढांचा स्पष्ट करता है कि प्रशासन विभिन्न भौगोलिक स्तरों पर किस प्रकार विभाजित और सुचारु रूप से संचालित है।

121. (A) जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक भागीदारी की प्रक्रिया को मजबूत करना।
स्थानीय स्वशासन की स्थापना का मूल विचार यह था कि विकास की योजनाएं उन लोगों द्वारा बनाई जानी चाहिए जो उनसे सीधे प्रभावित होते हैं। मध्य प्रदेश में पंचायतों और नगर निकायों के माध्यम से आम नागरिकों को शासन में सीधे भाग लेने का अवसर मिला है। इससे न केवल स्थानीय समस्याओं का समाधान शीघ्र होता है, बल्कि लोगों में राजनीतिक जागरूकता भी बढ़ती है। सत्ता का यह विकेंद्रीकरण ही लोकतंत्र को वास्तविक अर्थों में सफल बनाता है, जहाँ निर्णय लेने की शक्ति केवल राजधानी तक सीमित नहीं रहती है।

122. (A) आवश्यक नागरिक सेवाएं प्रदान करने के लिए संगठन और उसकी शक्तियां।
नगर निगम का प्राथमिक उत्तरदायित्व शहर के निवासियों को स्वच्छ वातावरण और बेहतर नागरिक सुविधाएं प्रदान करना है। कचरा प्रबंधन में विफलता और उसके परिणामस्वरूप होने वाला स्वास्थ्य संकट यह दर्शाता है कि निकाय अपने अनिवार्य कार्यों और शक्तियों का प्रभावी उपयोग करने में असमर्थ रहा है। यह स्थिति अक्सर वित्तीय संसाधनों की कमी, प्रशासनिक अकुशलता या खराब प्रबंधन के कारण उत्पन्न होती है। ऐसी विफलता स्थानीय शासन की विश्वसनीयता को प्रभावित करती है और सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लिए एक गंभीर चुनौती खड़ी करती है।

123. (A) केवल 1 और 3
पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण ने ग्रामीण मध्य प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया है। इस व्यवस्था ने लाखों महिलाओं को नेतृत्व की भूमिका में ला खड़ा किया है, जिससे वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुई हैं। महिला प्रतिनिधियों की उपस्थिति से स्थानीय शासन में पेयजल, स्वच्छता और शिक्षा जैसे मानवीय विकास के मुद्दों को अधिक प्राथमिकता मिलने लगी है। यद्यपि कुछ बाधाएं अब भी मौजूद हैं, लेकिन उनकी बढ़ती संख्या ने राज्य की राजनीति में एक सकारात्मक और अधिक संवेदनशील दृष्टिकोण विकसित करने में मदद की है।

124. (A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
विकास की राजनीति में संसाधनों का आवंटन हमेशा एक संवेदनशील विषय होता है क्योंकि राज्य के पास बजट सीमित होता है। जब सरकार किसी एक जिले के लिए अस्पताल या सड़क की घोषणा करती है, तो अन्य क्षेत्र अपनी उपेक्षा महसूस कर सकते हैं। यह प्रतिस्पर्धा समुदायों के बीच राजनीतिक खींचतान और विवाद को जन्म देती है। प्रत्येक समूह अपने क्षेत्र के लिए अधिक लाभ प्राप्त करना चाहता है, जिससे सरकार के लिए संतुलन बनाए रखना कठिन हो जाता है। अतः विकास के निर्णय अक्सर केवल आर्थिक नहीं बल्कि राजनीतिक रूप से भी चुनौतीपूर्ण होते हैं।

125. (B) संभाग के आयुक्त द्वारा
मध्य प्रदेश में प्रशासनिक नियंत्रण के पदानुक्रम में जिला कलेक्टर सीधे एक आयुक्त के प्रशासनिक पर्यवेक्षण में कार्य करता है। आयुक्त, जो एक पूरे संभाग का प्रमुख होता है, कलेक्टर के प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है और उसे आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान करता है। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि जिला प्रशासन राज्य सरकार की नीतियों के अनुरूप कार्य करे और विभिन्न जिलों के बीच बेहतर समन्वय बना रहे। आयुक्त का पद प्रशासन में एक महत्वपूर्ण समीक्षा और मार्गदर्शन की परत के रूप में कार्य करता है, जो शासन को अधिक सुव्यवस्थित बनाता है।

126. (C) निर्वाचित स्थानीय प्रतिनिधियों के अधिकार के अनुकूल होना और उनके साथ मिलकर काम करना।
स्थानीय शासन में नौकरशाही के लिए सबसे बड़ी चुनौती निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ तालमेल बिठाना है। अधिकारी नियमों और विनियमों के आधार पर कार्य करते हैं, जबकि प्रतिनिधि जनता की मांगों और राजनीतिक दबावों से प्रेरित होते हैं। कई बार इन दोनों के दृष्टिकोणों में भिन्नता के कारण प्रशासनिक अवरोध उत्पन्न होते हैं। एक सफल स्थानीय शासन के लिए यह आवश्यक है कि अधिकारी प्रतिनिधियों के लोकतांत्रिक जनादेश का सम्मान करें और प्रतिनिधि भी नियमों के महत्व को समझें। इन दोनों के बीच का संतुलन ही प्रभावी विकास सुनिश्चित करता है।

127. (B) विधायिका में पेश किए जाने वाले सरकारी विधेयकों का मसौदा तैयार करना।
सचिवालय का विधायी कार्यों में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। यद्यपि कानून बनाना विधान सभा का कार्य है, लेकिन उन कानूनों के लिए आवश्यक विस्तृत तकनीकी और कानूनी मसौदा तैयार करने का कार्य सचिवालय के अनुभवी अधिकारियों द्वारा किया जाता है। वे प्रस्तावित कानूनों के विभिन्न पहलुओं का

Downloaded from www.pdf.tube

किया जा सकता है। वहीं दूसरा पक्ष तर्क देता है कि जब तक प्रभावित क्षेत्रों में गरीबी और बेरोजगारी जैसी मूल समस्याओं को हल नहीं किया जाएगा, तब तक स्थाई शांति संभव नहीं है। अतः, एक प्रभावी रणनीति के रूप में विकास और सुरक्षा दोनों के बीच सही संतुलन बनाना राज्य सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती रही है।

93. (A) केवल 1 और 2
मुख्य सचिव का कार्यालय राज्य के विभिन्न विभागों के बीच तालमेल बनाए रखने और प्रशासन में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। जिला स्तर पर कलेक्टर राज्य सरकार का मुख्य प्रतिनिधि होता है जो शासन की योजनाओं को सीधे लागू करता है और स्थानीय स्थिति की जानकारी सरकार तक पहुँचाता है। हालांकि, सचिवालय प्रत्येक जिला मुख्यालय में नहीं होता; यह केवल राज्य की राजधानी में स्थित होता है। सचिवालय का कार्य नीति निर्धारण है, जबकि जिला प्रशासन का मुख्य कार्य क्षेत्रीय क्रियान्वयन है।

94. (D) सड़कों, स्ट्रीटलाइट्स और स्वच्छता जैसी स्थानीय बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना और उनका रखरखाव करना।
नगर पालिका परिषद के प्रभावी होने के लिए उसकी वित्तीय आत्मनिर्भरता अत्यंत आवश्यक है। पर्याप्त धन के बिना, वह अपने प्राथमिक कार्यों जैसे सफाई, पानी की आपूर्ति और सार्वजनिक रोशनी का रखरखाव नहीं कर सकती। वित्तीय स्वायत्तता उसे राज्य सरकार के अनुदानों पर कम निर्भर बनाती है और स्थानीय विकास के कार्यों में गति प्रदान करती है। यदि परिषद आर्थिक रूप से कमजोर है, तो शहरी बुनियादी ढांचा प्रभावित होता है, जिससे नागरिकों के दैनिक जीवन की गुणवत्ता में गिरावट आती है और विकास के लक्ष्य अधूरे रह जाते हैं।

95. (A) उनकी स्थिति को कल्याण के निष्क्रिय प्राप्तकर्ताओं से बदलकर राजनीतिक और विकास प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाना।
वंचित वर्गों के सशक्तिकरण का मूल विचार उन्हें केवल सहायता देने तक सीमित नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य उन्हें राजनीतिक रूप से इतना जागरूक और शक्तिशाली बनाना है कि वे स्वयं अपने अधिकारों की मांग कर सकें और शासन की निर्णय प्रक्रिया में प्रभावी भूमिका निभा सकें। जब ये वर्ग नीतियों को बनाने और उनके क्रियान्वयन में शामिल होते हैं, तभी उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में वास्तविक और स्थाई सुधार संभव होता है। यह प्रक्रिया लोकतंत्र को अधिक समावेशी और न्यायपूर्ण बनाने में सहायक है।

96. (A) 2, 3, 1
मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था के पदानुक्रम में सबसे छोटी और आधारभूत इकाई ग्राम पंचायत है जो एक गाँव के स्तर पर कार्य करती है। इसके बाद जनपद पंचायत आती है, जो कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक खंड के दायरे को कवर करती है। सबसे ऊपर जिला पंचायत स्थित होती है जिसका कार्य पूरे जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास कार्यों का समन्वय और निगरानी करना है। यह भौगोलिक विस्तार का क्रम शासन को विकेंद्रीकृत करने और जमीनी स्तर तक पहुँचाने के लिए वैज्ञानिक ढंग से बनाया गया है।

NODIA

97. (B) एक नए विश्वविद्यालय या एक प्रमुख औद्योगिक संयंत्र का स्थान।
विकास की राजनीति में संसाधनों और बड़ी परियोजनाओं का भौगोलिक वितरण अक्सर विवाद का कारण बनता है। जब सरकार किसी विशेष जिले में विश्वविद्यालय या बड़े कारखाने की घोषणा करती है, तो अन्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि भी अपने लिए वैसी ही मांग करते हैं। यह प्रतिस्पर्धा इस डर से उत्पन्न होती है कि किसी एक क्षेत्र का विकास दूसरे की उपेक्षा की कीमत पर न हो। ऐसी बहसें दर्शाती हैं कि विकास केवल आर्थिक मुद्दा नहीं है, बल्कि क्षेत्रीय गौरव और राजनीतिक प्रतिनिधित्व से भी गहराई से जुड़ा हुआ है।

98. (A) नीति निर्माण, समीक्षा और पर्यवेक्षण में मंत्रियों की सहायता करना।
सचिवालय मध्य प्रदेश की प्रशासनिक प्रणाली का मुख्य केंद्र है जहाँ विशेषज्ञ लोक सेवक मंत्रियों को जटिल नीतिगत विषयों पर परामर्श देते हैं। इसका मुख्य कार्य केवल आदेशों का पालन करना नहीं, बल्कि विभिन्न विकल्पों का विश्लेषण करना, नए कानूनों का मसौदा तैयार करना और सरकारी योजनाओं की प्रगति की निरंतर समीक्षा करना है। यह सुनिश्चित करता है कि सरकार के निर्णय प्रशासनिक और कानूनी रूप से सही हों। सचिवालय पूरे राज्य के प्रशासन के सुचारू संचालन के लिए दिशा-निर्देश जारी करने वाला महत्वपूर्ण संस्थान है।

99. (C) A सही है लेकिन R गलत है।
जिला कलेक्टर मध्य प्रदेश के प्रशासनिक ढांचे में एक अत्यंत शक्तिशाली और महत्वपूर्ण पद है। वह जिले की प्रशासनिक व्यवस्था का नेतृत्व करता है और उसके पास व्यापक कार्यकारी शक्तियां होती हैं। हालांकि, कलेक्टर का चयन जनता द्वारा सीधे चुनाव के माध्यम से नहीं किया जाता है; वह संघ या राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियुक्त एक पेशेवर लोक सेवक होता है। उसकी शक्ति और अधिकार संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों से आते हैं, जो उसे जिले में कानून-व्यवस्था और राजस्व का मुख्य अधिकारी बनाते हैं।

100. (D) आरक्षण के लिए संवैधानिक और वैधानिक प्रावधान।
स्थानीय निकायों में महिलाओं की बढ़ती संख्या 73वें और 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत किए गए आरक्षण के प्रावधानों का प्रत्यक्ष परिणाम है। मध्य प्रदेश ने इस दिशा में और आगे बढ़ते हुए स्थानीय चुनावों में महिलाओं के लिए 50% तक आरक्षण सुनिश्चित किया है। इन कानूनी सुरक्षा उपायों के बिना, पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं के लिए इतनी बड़ी संख्या में नेतृत्व के पदों तक पहुँचना बहुत कठिन होता। यह आरक्षण उन्हें सार्वजनिक जीवन में सक्रिय होने और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है।

101. (C) जनपद पंचायत
मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था के त्रि-स्तरीय ढांचे में 'जनपद पंचायत' को मध्यवर्ती या खंड स्तर के निकाय के

होता है जो विकास योजनाओं का संचालन करता है, तो दूसरी ओर वह राजस्व संग्रहण और भू-अभिलेखों के लिए उत्तरदायी है। जिला मजिस्ट्रेट के रूप में उसके पास कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए दंडाधिकारी शक्तियां भी होती हैं। यह शक्तियों का संगम उसे जिले में एक प्रभावशाली और केंद्रीय स्थान प्रदान करता है, जिससे वह आपातकालीन स्थितियों और सामान्य प्रशासन में त्वरित और प्रभावी निर्णय लेने में पूरी तरह सक्षम होता है।

137. (C) पड़ोसी देशों के साथ मध्य प्रदेश की विदेश नीति।
भारतीय संवैधानिक ढांचे के अनुसार, विदेश नीति और अंतरराष्ट्रीय संबंध पूरी तरह से केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। राज्य सरकारों के पास पड़ोसी देशों के साथ संधियाँ करने या विदेश नीति निर्धारित करने का कोई अधिकार नहीं है। मध्य प्रदेश की राजनीति मुख्य रूप से आंतरिक मुद्दों जैसे जनजातीय कल्याण, क्षेत्रीय विकास, सामाजिक सशक्तिकरण और आंतरिक सुरक्षा तक ही सीमित रहती है। अतः, विदेश नीति राज्य के राजनीतिक परिदृश्य का हिस्सा नहीं है, क्योंकि यह केंद्र का अनन्य विषय है जिसका निर्णय संघ स्तर पर लिया जाता है।

138. (A) P-4, Q-1, R-2, S-3
विकास की राजनीति का एक सामान्य उदाहरण चुनाव से पहले लोक-लुभावन घोषणाएं करना है ताकि मतदाताओं का समर्थन हासिल किया जा सके। महिलाओं का राजनीति में योगदान महत्वपूर्ण नेत्रियों के रूप में देखा जा सकता है जिन्होंने शीर्ष राजनीतिक पद संभाले। कलेक्टर की भूमिका जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसी आवश्यक सेवाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण होती है। नक्सली मुद्दा मुख्य रूप से विशिष्ट जिलों में सुरक्षा और शांति बहाली के प्रयासों से गहराई से जुड़ा हुआ है, जो राज्य प्रशासन के लिए एक प्रमुख सुरक्षा चुनौती है।

139. (B) वे सिद्धांत जो राज्य और स्थानीय स्वशासन निकायों के बीच निधियों के वितरण को नियंत्रित करेंगे।
राज्य वित्त आयोग एक महत्वपूर्ण संवैधानिक निकाय है जो स्थानीय शासन को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए कार्य करता है। इसका मुख्य कार्य यह निर्धारित करना है कि राज्य सरकार द्वारा एकत्रित करों का कितना हिस्सा पंचायतों और नगरपालिकाओं को दिया जाना चाहिए। इसके अलावा, यह आयोग स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति को सुधारने के उपायों और राज्य की संचित निधि से उन्हें दी जाने वाली सहायता अनुदान के बारे में भी महत्वपूर्ण अनुशंसाएं करता है। यह स्वायत्तता और प्रभावी विकेंद्रीकरण सुनिश्चित करने के लिए अपरिहार्य है।

140. (A) केवल 1 और 2
मध्य प्रदेश में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन एक त्रि-स्तरीय पदानुक्रम पर आधारित है, जिसमें ग्राम, खंड और जिला स्तर पर निर्वाचित निकाय होते हैं। इन निकायों को संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में उल्लिखित 29 विषयों पर कार्य करने और निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है। हालांकि, इन निकायों का नेतृत्व मुख्य सचिव द्वारा नियुक्त अधिकारियों द्वारा नहीं किया जाता, बल्कि इनके अध्यक्ष जनता या निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। सरकारी अधिकारी केवल उनकी प्रशासनिक सहायता और नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए तैनात होते हैं।

141. (B) सरकार के एक विशिष्ट विभाग का प्रशासनिक प्रमुख और विशेषज्ञ सलाहकार।
सचिवालय में सचिव का पद विशेषज्ञता और अनुभव का संगम है। वह एक वरिष्ठ लोक सेवा अधिकारी होता है जो अपने आवंटित विभाग के समग्र प्रशासन की देखरेख करता है। उसका मुख्य कार्य संबंधित मंत्री को नीति निर्माण के लिए आवश्यक डेटा, कानूनी बारीकियां और विभिन्न प्रशासनिक विकल्पों की जानकारी देना है। सचिव यह सुनिश्चित करता है कि विभाग का बजट सही ढंग से खर्च हो और सरकारी नियम पूरी तरह लागू हों। वह राजनीति से दूर रहकर शासन की निरंतरता और प्रशासनिक कुशलता को बनाए रखने का महत्वपूर्ण कार्य करता है।

142. (B) वन संसाधनों पर उनके पारंपरिक अधिकारों को पहचानना और सुरक्षित करना।
जनजातीय सशक्तिकरण का सबसे महत्वपूर्ण पहलू उनकी पहचान और उनकी भूमि से जुड़ाव को सुरक्षित करना है। मध्य प्रदेश में बड़ी जनजातीय आबादी है जो अपनी आजीविका के लिए वनों पर निर्भर है। उनके सशक्तिकरण में वन अधिकार अधिनियम का क्रियान्वयन अत्यंत आवश्यक है, ताकि उन्हें लघु वनोपज एकत्र करने और अपने पारंपरिक संसाधनों पर अधिकार मिल सके। यह उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाता है और बाहरी शोषण से रक्षा करता है। यह अधिकार उनके स्वाभिमान और सामाजिक विकास की दिशा में एक बड़ा और ठोस कदम है।

143. (A) विकास के लिए संपर्क में सुधार करना और सुरक्षा बलों की आवाजाही को सुगम बनाना।
नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण एक रणनीतिक निर्णय है। अच्छी सड़कें न केवल स्थानीय ग्रामीणों को बाजारों, स्कूलों और अस्पतालों से जोड़ती हैं, बल्कि वे सुरक्षा बलों को आपातकालीन स्थितियों में त्वरित कार्रवाई करने में भी मदद करती हैं। संपर्क बढ़ने से इन क्षेत्रों का अलगाव कम होता है और चरमपंथी विचारधारा का प्रभाव कमजोर पड़ता है। इस प्रकार, बुनियादी ढांचे का विस्तार सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और विकास की प्रक्रिया को सुदूर गाँवों तक पहुँचाने के बीच एक अनिवार्य सेतु की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

144. (D) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।
जिला पंचायत का प्रशासनिक नेतृत्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा किया जाता है, जो सामान्यतः एक भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है। हालांकि कलेक्टर जिले का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है, लेकिन जिला पंचायत के दैनिक कार्यों और ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए एक अलग समर्पित अधिकारी की व्यवस्था की गई है। यह कार्य विभाजन कलेक्टर के कार्यभार

Click Here to Buy book on Amazon

को कम करने और जिला पंचायत को अधिक विशिष्ट ध्यान और प्रशासनिक समय प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया है। कलेक्टर और सीईओ विकास हेतु समन्वय करते हैं।

145. (A) राज्य सरकार का अत्यधिक नियंत्रण और उस पर वित्तीय निर्भरता।
स्थानीय निकायों की स्वायत्तता में सबसे बड़ी बाधा उनकी आर्थिक स्थिति है। यद्यपि उन्हें स्वतंत्र निकाय माना जाता है, लेकिन उनके पास स्वयं के राजस्व के बहुत सीमित स्रोत हैं। वे अपने अधिकांश विकास कार्यों और यहाँ तक कि कर्मचारियों के वेतन के लिए भी राज्य सरकार से मिलने वाले अनुदानों और वित्तीय आवंटन पर निर्भर रहते हैं। इस वित्तीय निर्भरता के कारण राज्य सरकार का प्रशासनिक नियंत्रण बढ़ जाता है, जिससे स्थानीय निकाय अपनी स्वतंत्र प्राथमिकताएं तय करने और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार त्वरित निर्णय लेने में अक्सर असमर्थ रहते हैं।

146. (B) एक राजनीतिक दल द्वारा अपने चुनावी घोषणा पत्र में किसानों को निःशुल्क बिजली देने का वादा करना।
'विकास की राजनीति' का अर्थ विकास से जुड़ी योजनाओं का उपयोग राजनीतिक समर्थन और वोट जुटाने के लिए करना है। किसानों को मुफ्त बिजली या कर्ज माफी जैसे वादे सीधे तौर पर मतदाताओं को प्रभावित करने की रणनीति का हिस्सा होते हैं। ये घोषणाएं दर्शाती हैं कि संसाधनों का वितरण केवल आर्थिक आवश्यकताओं पर नहीं, बल्कि राजनीतिक लाभ और चुनावी समीकरणों को ध्यान में रखकर तय किया जाता है। ऐसी नीतियां अक्सर चुनावी विमर्श का मुख्य केंद्र होती हैं और राज्य की राजनीति की दिशा और गति को निर्धारित करती हैं।

147. (A) राजनीतिक कार्यपालिका और स्थायी कार्यपालिका।
महापौर जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि हैं जो राजनीतिक प्राथमिकताओं को दर्शाते हैं, जबकि नगर निगम आयुक्त एक स्थायी लोक सेवक हैं जो नियमों और बजटीय सीमाओं के अनुसार कार्य करते हैं। इन दोनों के बीच टकराव अक्सर तब होता है जब राजनीतिक इच्छाशक्ति और प्रशासनिक नियमों या वित्तीय बाधाओं के बीच असहमति होती है। यह स्थिति शहरी शासन की एक अंतर्निहित चुनौती है जहाँ लोकतांत्रिक आकांक्षाओं और प्रशासनिक वास्तविकता के बीच संतुलन बनाना आवश्यक होता है। सफल शासन के लिए इन दोनों अंगों के बीच सहयोग अनिवार्य है।

148. (B) A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या है।
पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण ने ग्रामीण राजनीति में उनकी दृश्यता को निश्चित रूप से बढ़ाया है। अब लाखों महिलाएं सरपंच और सदस्य के रूप में शासन में भाग ले रही हैं, जो एक बड़ा सामाजिक परिवर्तन है। हालांकि, ऐसी प्रथाएं, जहाँ निर्वाचित महिला के स्थान पर उसका पति या पुरुष रिश्तेदार वास्तविक शक्ति का प्रयोग करता है, आज भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। यह दर्शाता है कि केवल कानूनी आरक्षण ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि महिलाओं के वास्तविक सशक्तिकरण के लिए सामाजिक मानसिकता में बदलाव और उन्हें प्रशासनिक प्रशिक्षण देना भी आवश्यक है।

149. (B) जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक
जिले में कानून और व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी एक सामूहिक और समन्वित कार्य है। जिला मजिस्ट्रेट के पास दंडाधिकारी शक्तियां होती हैं और वह जिले की सामान्य सुरक्षा नीति निर्धारित करता है। पुलिस अधीक्षक पुलिस बल का प्रमुख होता है और वह जमीनी स्तर पर अपराध नियंत्रण और शांति व्यवस्था लागू करने के लिए उत्तरदायी है। ये दोनों अधिकारी निरंतर संपर्क में रहकर काम करते हैं। उनके बीच का प्रभावी सामंजस्य ही जिले में सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करता है और किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए अत्यंत आवश्यक है।

150. (A) 3, 1, 4, 2
मध्य प्रदेश के प्रशासनिक पदानुक्रम में मुख्य सचिव पूरे राज्य के प्रशासन का समन्वय करता है, जो सर्वोच्च स्तर है। इसके बाद कलेक्टर आता है, जिसका प्रभाव क्षेत्र एक पूरा जिला होता है। जनपद पंचायत का मुख्य कार्यपालन अधिकारी खंड स्तर पर कार्य करता है, जो जिले का एक उप-भाग है। सबसे निचले और स्थानीय स्तर पर सरपंच होता है जिसका अधिकार क्षेत्र केवल एक विशिष्ट ग्राम पंचायत या गाँव तक सीमित होता है। यह अनुक्रम राज्य में शक्ति और प्रशासनिक नियंत्रण के विस्तार को पूरी तरह स्पष्ट करता है।

151. (C) राज्य की संपूर्ण सिविल सेवा के प्रमुख और मंत्रिमंडल के सचिव।
मुख्य सचिव का पद राज्य प्रशासनिक व्यवस्था का शिखर है। वह न केवल सभी लोक सेवकों का मार्गदर्शन और नियंत्रण करता है, बल्कि वह राजनीतिक सरकार और स्थायी प्रशासन के बीच मुख्य कड़ी भी होता है। मंत्रिमंडल की बैठकों का एजेंडा तैयार करना और लिए गए निर्णयों का रिकॉर्ड रखना उसी की जिम्मेदारी है। वह मुख्यमंत्री का सबसे भरोसेमंद प्रशासनिक सलाहकार होता है। उसकी प्रभावी भूमिका पर ही राज्य सरकार की नीतियों की सफलता और संपूर्ण प्रशासनिक मशीनरी की कार्यक्षमता और अनुशासन पूरी तरह निर्भर करता है।

152. (C) ग्रामीण स्थानीय स्वशासन
भारतीय संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम ऐतिहासिक रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए समर्पित है। मध्य प्रदेश में इस अधिनियम ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की, जिससे ग्राम, जनपद और जिला पंचायतों का गठन अनिवार्य हो गया। इसने इन निकायों को नियमित चुनाव, निश्चित कार्यकाल और विकास के लिए वित्तीय शक्तियां प्रदान कीं। इस कानून का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण समुदायों को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें अपने क्षेत्र की विकास योजनाओं को स्वयं तैयार करने और क्रियान्वित करने की शक्ति प्रदान करना है।

153. (A) केवल 2
मध्य प्रदेश में कलेक्टर का पद एक अत्यंत महत्वपूर्ण कड़ी है जो राज्य सरकार के निर्देशों को जिला स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करती है। यह पद आजादी से बहुत पहले प्रशासनिक सुधारों के दौरान राजस्व संग्रहण के लिए बनाया गया था।

NODIA

कलेक्टर की भूमिका आपदा प्रबंधन में भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह जिले में सभी राहत और बचाव कार्यों का मुख्य समन्वयक होता है। वह राज्य सरकार को जिले की वास्तविक स्थिति से अवगत कराता है, जिससे नीतियों के निर्माण और उनमें आवश्यक संशोधन करने में सरकार को महत्वपूर्ण सहायता प्राप्त होती है।

154. (A) व्यापक राजनीतिक एजेंडे के हिस्से के रूप में आर्थिक सशक्तिकरण।
पिछड़े वर्गों को ऋण पर सहायता प्रदान करना राज्य सरकार की एक सोची-समझी नीति है जिसका उद्देश्य उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। यह सशक्तिकरण का एक ऐसा रूप है जो केवल राजनीतिक भागीदारी से आगे बढ़कर उनकी आजीविका और जीवन स्तर में सुधार पर ध्यान केंद्रित करता है। ऐसी योजनाएं सामाजिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त करने और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक हैं। यह राजनीतिक दलों के लिए समाज के एक बड़े वर्ग का विश्वास जीतने और समावेशी विकास का दावा करने का एक प्रभावी और सशक्त माध्यम भी है।

155. (A) P-3, Q-4, R-1, S-2
महापौर नगर निगम के निर्वाचित प्रमुख हैं जो शहरी नागरिक प्रशासन का नेतृत्व करते हैं। सचिव सचिवालय में विभाग के प्रशासनिक प्रमुख होते हैं जहाँ नीतियां बनाई जाती हैं। सरपंच ग्राम पंचायत के प्रधान होते हैं जो गाँव के विकास कार्यों के लिए सीधे जिम्मेदार हैं। कलेक्टर जिला प्रशासन की धुरी है जो कानून-व्यवस्था और राजस्व के साथ-साथ जिले की समस्त गतिविधियों का समन्वय करता है। यह मिलान शासन के विभिन्न स्तरों और उनसे जुड़े महत्वपूर्ण पदों के बीच के स्पष्ट कार्यात्मक और प्रशासनिक संबंधों को पूर्णतः प्रदर्शित करता है।

156. (B) मुख्य कार्यपालन अधिकारी और मुख्य नगरपालिका अधिकारी जैसे अधिकारी जो स्थायी सरकारी सेवा का हिस्सा हैं।
स्थानीय शासन में 'नौकरशाही' का तात्पर्य उन प्रशिक्षित पेशेवरों से है जो शासन की निरंतरता बनाए रखते हैं। ये अधिकारी राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और इनका मुख्य कार्य निर्वाचित प्रतिनिधियों को कानूनी और तकनीकी सलाह देना है। वे यह सुनिश्चित करते हैं कि पंचायत या नगरपालिका के निर्णय सरकारी नियमों और बजट की सीमाओं के भीतर हों। निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल निश्चित होता है, लेकिन नौकरशाही एक स्थायी ढांचा है जो योजनाओं के दीर्घकालिक और सुचारु निष्पादन के लिए आवश्यक विशेषज्ञता और अनुभव प्रदान करती है।

157. (C) महिलाओं ने राज्य विधानसभा में 100% प्रतिनिधित्व प्राप्त कर लिया है।
मध्य प्रदेश की राजनीति में महिलाओं की भागीदारी निरंतर बढ़ रही है, लेकिन राज्य विधानसभा में उनका प्रतिनिधित्व अभी भी पूर्ण नहीं है। हालांकि स्थानीय निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण प्राप्त है, जिससे वहां उनकी संख्या बढ़ी है, लेकिन विधायी स्तर पर उनकी उपस्थिति अभी भी सीमित है। अन्य विकल्प सही हैं क्योंकि राज्य में बड़ी जनजातीय आबादी है, कुछ जिलों में नक्सली समस्या एक चुनौती है और विकास की राजनीति चुनावी विमर्श का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और सक्रिय हिस्सा बनी हुई है, जो शासन की दिशा तय करती है।

158. (A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
सचिवालय मध्य प्रदेश के प्रशासन का 'मस्तिष्क' है जहाँ राज्यव्यापी महत्व के निर्णय लिए जाते हैं। यहाँ के अधिकारियों के पास प्रशासन का व्यापक अनुभव और तकनीकी ज्ञान होता है, जो मंत्रियों को सटीक नीतिगत विकल्प पेश करने में मदद करता है। किसी भी नए कानून या योजना की रूपरेखा यहीं तैयार होती है। मंत्रियों के पास राजनीतिक दृष्टि होती है, लेकिन उसे व्यावहारिक और कानूनी रूप प्रदान करने का कार्य सचिवालय ही करता है। अतः, राज्य के शासन और विकास की दिशा निर्धारित करने में इसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है।

159. (D) राज्य पुलिस बल का प्रशासन।
नगर निगम का कार्यक्षेत्र मुख्य रूप से शहर की नागरिक सुविधाओं और स्थानीय विकास तक सीमित होता है। इसमें सड़कों का निर्माण, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता प्रबंधन और जल आपूर्ति जैसे अनिवार्य कार्य शामिल हैं। हालांकि, राज्य पुलिस बल का प्रशासन और नियंत्रण पूरी तरह से राज्य सरकार के गृह विभाग के अधीन होता है, न कि नगर निगम के। नगर निगम केवल यातायात और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस की सहायता ले सकता है, लेकिन पुलिस बल का प्रबंधन और परिचालन स्वायत्तता उसके अधिकार क्षेत्र से पूर्णतः बाहर है।

160. (D) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।
विकास कभी भी राजनीति से अलग नहीं होता है, क्योंकि संसाधनों का आवंटन और परियोजनाओं का चयन समाज की राजनीतिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। मध्य प्रदेश में राजनीतिक दल विकास को एक उपकरण के रूप में उपयोग करते हैं ताकि वे अपनी कार्यकुशलता दिखा सकें और चुनावी समर्थन प्राप्त कर सकें। विकास परियोजनाओं का श्रेय लेना और उन्हें अपने लक्ष्यों के अनुसार नियोजित करना राजनीति का एक स्वीकृत हिस्सा है। अतः, विकास की राजनीति में तकनीकी आवश्यकताएं और राजनीतिक उद्देश्य दोनों मिलकर शासन की दिशा तय करते हैं।

161. (B) राजनीति में विशिष्ट सामाजिक मुद्दों को उजागर करने में महिलाओं का योगदान।
जब कोई महिला नेता विधानसभा में वेतन असमानता जैसे विषयों पर प्रश्न उठाती है, तो वह राजनीति में एक नया और संवेदनशील दृष्टिकोण लाती है। अक्सर ऐसे मुद्दे जो सीधे महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक अधिकारों से जुड़े होते हैं, पुरुष प्रधान विमर्श में उपेक्षित रह जाते हैं। उनकी सक्रियता से इन महत्वपूर्ण विषयों पर विधायी चर्चा होती है और सरकार पर नई नीतियां बनाने का दबाव बढ़ता है। यह दर्शाता है कि राजनीति में महिलाओं की उपस्थिति केवल संख्यात्मक नहीं है,

Downloaded from www.pdf.tube

और आपातकालीन स्थितियों में त्वरित निर्णय लेने के लिए सर्वशक्तिमान प्रशासनिक प्राधिकारी माना जाता है।

179. (B) स्थानीय स्वशासन में वित्तीय स्वायत्तता की कमी।
यदि कोई नगर निगम अपने कर्मचारियों को वेतन देने में असमर्थ है, तो यह उसकी आर्थिक पराधीनता का एक गंभीर संकेत है। मध्य प्रदेश में कई नगरीय निकाय अपने राजस्व के लिए पूरी तरह से राज्य सरकार के अनुदानों पर निर्भर हैं। जब इन अनुदानों में देरी होती है या वे पर्याप्त नहीं होते, तो अनिवार्य नागरिक सेवाएं बाधित हो जाती हैं। यह स्थिति स्पष्ट करती है कि बिना सुदृढ़ और स्वतंत्र वित्तीय स्रोतों के, स्थानीय स्वशासन का ढांचा कमजोर रहता है और वह अपनी बुनियादी जिम्मेदारियों को निभाने में भी पूरी तरह विफल हो सकता है।

180. (A) राज्य की कार्यकारी और प्रशासनिक मशीनरी।
मुख्य सचिव की नियुक्ति राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू और प्रभावी बनाने के लिए की जाती है। चूंकि वह वरिष्ठतम लोक सेवा अधिकारी होता है, इसलिए उसे प्रशासन का व्यापक अनुभव होता है। मुख्यमंत्री उसे इसलिए चुनते हैं ताकि सरकार की नीतियों को नौकरशाही के माध्यम से कुशलतापूर्वक लागू किया जा सके। यह पद न केवल सचिवालय का नेतृत्व करता है, बल्कि यह पूरे राज्य की लोक सेवा में अनुशासन और तालमेल बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। यह प्रशासनिक नेतृत्व और राजनीतिक इच्छाशक्ति के बीच संतुलन बनाने वाली सर्वोच्च कार्यकारी भूमिका है।

181. (A) कल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी और भ्रष्टाचार मुक्त क्रियान्वयन।
वंचित वर्गों के सशक्तिकरण के लिए धन और योजनाओं की कमी से बड़ी चुनौती उनका ईमानदारी से जनता तक पहुँचना है। अक्सर प्रशासनिक जटिलताओं, बिचौलियों के हस्तक्षेप और स्थानीय स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण पात्र व्यक्ति लाभ से वंचित रह जाते हैं। योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता लाना और जवाबदेही तय करना राज्य सरकार के लिए एक कठिन कार्य है। सशक्तिकरण तभी वास्तविक होगा जब तंत्र इतना कुशल हो कि विकास का अंतिम लाभ बिना किसी अवरोध के समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति तक प्रभावी ढंग से पहुँच सके।

182. (A) 1, 2, 4, 3
प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र की दृष्टि से मुख्य सचिव राज्य का सर्वोच्च अधिकारी है। उसके बाद विभिन्न विभागों के सचिव आते हैं जो राज्य स्तरीय नीतियों के लिए जिम्मेदार हैं। संभाग स्तर पर आयुक्त का स्थान होता है जो सचिव के मार्गदर्शन में कार्य करता है लेकिन कलेक्टर से वरिष्ठ होता है। पदानुक्रम में जिला स्तर पर कलेक्टर की स्थिति आती है, जो क्षेत्रीय क्रियान्वयन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। यह अवरोही क्रम स्पष्ट करता है कि मध्य प्रदेश में प्रशासनिक शक्ति किस प्रकार शीर्ष से नीचे की ओर प्रवाहित होती है, जिससे सुशासन संभव होता है।

183. (A) विकास संबंधी निर्णय राजनीतिक उद्देश्यों से प्रभावित होते हैं और उनके लिए उपयोग किए जाते हैं।
विकास की राजनीति का अर्थ है कि विकास कार्य केवल तकनीकी आवश्यकता नहीं, बल्कि चुनावी विमर्श का केंद्र होते हैं। राजनीतिक दल मतदाताओं का समर्थन पाने के लिए विशिष्ट क्षेत्रों में सड़कों, स्कूलों और अस्पतालों जैसी परियोजनाओं को प्राथमिकता देते हैं। विकास के इन कार्यों को अक्सर राजनीतिक उपलब्धियों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रक्रिया में यह तय करना कि संसाधन कहाँ और किसके लिए खर्च होंगे, एक गहरा राजनीतिक निर्णय होता है जो मतदाताओं के व्यवहार और राज्य की सत्ता संरचना को सीधे और महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है।

184. (A) जमीनी स्तर की राजनीति और शासन में महिलाओं का योगदान।
जब एक महिला सरपंच स्वच्छता जैसे बुनियादी मुद्दे पर गाँव का नेतृत्व करती है, तो वह यह सिद्ध करती है कि स्थानीय शासन में महिलाओं की उपस्थिति गुणात्मक सुधार लाती है। उनकी संवेदनशीलता और सामुदायिक जुड़ाव उन्हें जटिल सामाजिक समस्याओं को हल करने में अधिक प्रभावी बनाता है। यह उदाहरण दर्शाता है कि आरक्षण ने न केवल महिलाओं को राजनीतिक अधिकार दिए हैं, बल्कि उन्हें सामाजिक परिवर्तन का शक्तिशाली वाहक भी बना दिया है। उनके ऐसे प्रयास ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता सुधारने और भविष्य के महिला नेतृत्व को प्रेरित करने में अत्यंत सहायक हैं।

185. (A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
कलेक्टर का पद मध्य प्रदेश के जिला प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है क्योंकि उसकी शक्तियां और जिम्मेदारियां अत्यंत व्यापक हैं। वह न केवल सरकारी राजस्व का संरक्षक है, बल्कि जिले में शांति बनाए रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग भी करता है। आधुनिक समय में, वह केंद्र और राज्य की सभी विकास योजनाओं के क्रियान्वयन की धुरी बन गया है। जिले की हर छोटी-बड़ी गतिविधि के लिए वह सरकार के प्रति पूर्णतः उत्तरदायी होता है, जो उसे जिले का वास्तविक प्रशासनिक और कार्यकारी केंद्र बनाता है।

186. (D) राज्य का वार्षिक बजट पारित करना।
ग्राम पंचायत की शक्तियां स्थानीय विकास और ग्रामीण कल्याण तक सीमित होती हैं। वह गाँवों में सड़कों का निर्माण, प्राथमिक शिक्षा की निगरानी और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लाभार्थियों की पहचान जैसे महत्वपूर्ण कार्य करती है। हालांकि, राज्य का वार्षिक बजट पारित करना एक विधायी कार्य है जो केवल मध्य प्रदेश विधान सभा के अधिकार क्षेत्र में आता है। ग्राम पंचायत केवल अपने स्वयं के आय-व्यय का विवरण तैयार कर सकती है और उसे ग्राम सभा से अनुमोदित करवा सकती है, लेकिन पूरे राज्य के वित्त पर उसका कोई वैधानिक नियंत्रण नहीं होता।

187. (B) केवल 2 और 3
मुख्य सचिव राज्य का प्रशासनिक प्रमुख होता है, जबकि मुख्यमंत्री राज्य का राजनीतिक प्रमुख होता है। सचिवों की

NODIA

यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि ग्रामीण विकास के निर्णय स्वयं ग्रामीणों द्वारा लिए जाएं, जिससे शासन में पारदर्शिता आती है और स्थानीय समस्याओं का समाधान त्वरित और अधिक प्रभावी ढंग से हो पाता है।

171. (A) शहरी राजनीति में महिलाओं की बढ़ती भूमिका और योगदान।
एक प्रमुख शहर की महापौर के रूप में महिला का चुना जाना यह प्रदर्शित करता है कि शहरी क्षेत्रों में नेतृत्व की धारणा बदल रही है। यह न केवल महिलाओं की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं और बढ़ती जागरुकता का परिणाम है, बल्कि यह समाज की उनके नेतृत्व के प्रति स्वीकृति को भी दर्शाता है। महिला महापौर अक्सर शहर के विकास के साथ-साथ महिला सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मानवीय पहलुओं पर अधिक ध्यान देती हैं। यह उपलब्धि राज्य के शहरी शासन को अधिक समावेशी और संतुलित बनाने की दिशा में एक बड़ा और सकारात्मक कदम माना जाता है।

172. (A) विभिन्न सरकारी विभागों के बीच प्रयासों के दोहराव और संघर्षों को रोकना।
जिला स्तर पर दर्जनों सरकारी विभाग स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, जिससे अक्सर कार्यों के दोहराव या क्षेत्राधिकार संबंधी विवादों की संभावना बनी रहती है। कलेक्टर एक मुख्य अधिकारी के रूप में कार्य करता है जो इन सभी विभागों को एक मंच पर लाता है। वह यह सुनिश्चित करता है कि सभी विभाग जिले के सर्वांगीण विकास के एक साझा लक्ष्य की ओर बढ़ें। इस समन्वय के बिना, सरकारी संसाधनों की बर्बादी हो सकती है और विकास परियोजनाओं की गति धीमी पड़ सकती है। अतः, कलेक्टर की समन्वयक की भूमिका प्रशासनिक दक्षता के लिए आधारभूत है।

173. (A) P-4, Q-1, R-2, S-3
राज्य स्तर पर मुख्य सचिव सर्वोच्च प्रशासनिक पद है जो पूरी मशीनरी का समन्वय करता है। संभागीय स्तर पर आयुक्त की भूमिका महत्वपूर्ण होती है जो कई जिलों की देखरेख करता है। जिला स्तर पर कलेक्टर मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है जो शासन की नीतियों को क्षेत्रीय स्तर पर लागू करता है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत एक निर्वाचित निकाय है जो ग्रामीण विकास और स्थानीय प्रशासन को सीधे संचालित करती है। यह संरचना प्रशासन को शीर्ष से लेकर जमीनी स्तर तक सुव्यवस्थित और प्रभावी ढंग से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य करती है।

174. (B) कानूनी ढांचे के भीतर, स्थानीय मामलों पर अपने निर्णय लेना और अपना स्वयं का धन जुटाना।
नगर निगम के लिए स्वायत्तता का अर्थ यह है कि वह अपने शहर की विशिष्ट आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से समझने और तदनुसार योजना बनाने के लिए स्वतंत्र हो। इसमें सड़कों, पार्कों और सफाई व्यवस्था पर स्वतंत्र निर्णय लेना शामिल है। इसके साथ ही, स्वायत्तता का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि निगम के पास अपने स्वयं के राजस्व स्रोत हों ताकि वह राज्य सरकार की वित्तीय मदद पर पूरी तरह निर्भर न रहे। यह शक्ति उन्हें एक आत्मनिर्भर और उत्तरदायी स्थानीय सरकार के रूप में विकसित होने में मदद करती है, जिससे जन-कल्याण सुगम होता है।

175. (B) सुरक्षा बल अभियान और सामाजिक-आर्थिक विकास पहल।
नक्सली समस्या के समाधान के लिए राज्य सरकार एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाती है। इसमें एक ओर सुरक्षा बलों के माध्यम से हिंसा को नियंत्रित करना और शांति स्थापित करना शामिल है, तो दूसरी ओर उन क्षेत्रों में सड़क, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुँचाना अनिवार्य है। केवल पुलिस कार्रवाई से इस समस्या का स्थाई हल नहीं निकल सकता, क्योंकि चरमपंथ अक्सर विकास की कमी और उपेक्षा से उत्पन्न होता है। अतः, सुरक्षा और विकास का यह समन्वय ही जनता का विश्वास जीतने और समस्या को जड़ से मिटाने का प्रभावी उपाय है।

176. (B) राज्य सरकार के विभागों का वह समूह, जिसका नेतृत्व सचिव करते हैं और जो मंत्रियों की सहायता करता है।
सचिवालय मध्य प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था का वह केंद्र है जहाँ सरकार की समस्त नीतियों का प्रारूप तैयार किया जाता है। यह किसी एक इमारत का नाम नहीं, बल्कि उन सभी मंत्रालयों और विभागों का सामूहिक ढांचा है जहाँ वरिष्ठ लोक सेवक कार्यरत होते हैं। उनका मुख्य कार्य मंत्रियों को प्रशासनिक डेटा, कानूनी परामर्श और तकनीकी जानकारी प्रदान करना है ताकि वे प्रभावी निर्णय ले सकें। सचिवालय यह सुनिश्चित करता है कि शासन के सभी अंग सुव्यवस्थित तरीके से कार्य करें और राज्य के विकास के लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके।

177. (A) उन्हें उनके क्षेत्रों में सामुदायिक संसाधनों और शासन पर नियंत्रण देना।
पेसा अधिनियम जनजातीय सशक्तिकरण का एक क्रांतिकारी कानून है जो पारंपरिक ग्राम सभाओं को अभूतपूर्व शक्तियां प्रदान करता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जनजातीय समुदायों के जल, जंगल और जमीन जैसे संसाधनों पर उनका प्राथमिक अधिकार बना रहे। यह उन्हें अपने स्थानीय विवादों को सुलझाने, लघु वनोपज का प्रबंधन करने और विकास परियोजनाओं के लिए अपनी सहमति देने की शक्ति प्रदान करता है। यह कानून उन्हें बाहरी हस्तक्षेप से बचाता है और उन्हें अपनी सांस्कृतिक पहचान के साथ स्वयं को विकसित करने का वास्तविक अवसर देता है।

178. (D) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।
जिला कलेक्टर केवल एक न्यायिक अधिकारी नहीं है, बल्कि उसके पास जिले के सर्वांगीण प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। वह जिला मजिस्ट्रेट के रूप में शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखता है, राजस्व संग्रहण की देखरेख करता है और जिले में सभी विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं का मुख्य समन्वयक होता है। उसकी भूमिका दंडाधिकारी और कार्यकारी शक्तियों का एक अनूठा संगम है। कलेक्टर जिले में राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है

Click Here to Buy book on Amazon

सुनिश्चित करती है कि प्रशासन का आकार और उसकी वित्तीय शक्तियां उस क्षेत्र की विशिष्ट नागरिक आवश्यकताओं और शहरी प्रबंधन की जटिलताओं के पूर्णतः अनुरूप हों ताकि विकास संभव हो सके।

196. (A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
स्थानीय स्वशासन के सफल संचालन के लिए नौकरशाही की विशेषज्ञता अपरिहार्य है। निर्वाचित प्रतिनिधि जनता की इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन उन्हें सरकारी नियमों, वित्तीय प्रक्रियाओं और कानूनी बारीकियों की गहरी समझ नहीं होती। यहीं पर पेशेवर अधिकारियों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, जो इन योजनाओं को तकनीकी रूप से व्यवहार्य बनाते हैं। यद्यपि अधिकारियों और प्रतिनिधियों के बीच कभी-कभी शक्ति को लेकर संघर्ष होता है, फिर भी इन दोनों का सहयोग ही एक पारदर्शी और कुशल स्थानीय प्रशासन सुनिश्चित करने का एकमात्र मार्ग है जिससे जन-कल्याण हो।

197. (C) सुदूर, वन और अविकसित आदिवासी बहुल क्षेत्र
मध्य प्रदेश में नक्सली गतिविधियाँ मुख्य रूप से उन भौगोलिक क्षेत्रों में केंद्रित हैं जो घने जंगलों से ढके हैं और जहाँ विकास की पहुँच अब तक सीमित रही है। इन सुदूर आदिवासी अंचलों में गरीबी, शिक्षा की कमी और शासन की कम उपस्थिति का लाभ उठाकर उग्रवादी अपनी विचारधारा फैलाते हैं। विशिष्ट जिलों के कुछ हिस्से इसी श्रेणी में आते हैं। इस चुनौती से निपटने के लिए सरकार इन क्षेत्रों में सुरक्षा बढ़ाने के साथ-साथ सड़क, बिजली और रोजगार जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुँचाने पर विशेष जोर दे रही है ताकि वे मुख्यधारा से जुड़ सकें।

198. (B) ऐतिहासिक सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन।
पिछड़े वर्गों के सशक्तिकरण का केंद्र उन बाधाओं को दूर करना है जिन्होंने पीढ़ियों से इन समूहों को विकास की दौड़ में पीछे रखा है। यह केवल आरक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें समान अवसर, बेहतर शिक्षा और आर्थिक संसाधन प्रदान करना भी इसमें शामिल है। इसका उद्देश्य समाज में एक ऐसा संतुलन बनाना है जहाँ जन्म या जाति किसी व्यक्ति की प्रगति में रुकावट न बने। यह राजनीतिक विमर्श राज्य में सामाजिक न्याय की स्थापना और समाज के सभी वर्गों के समावेशी विकास को सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है।

199. (B) महिलाओं की सुरक्षा और संपत्ति के अधिकारों से संबंधित कानूनों के लिए सफल पैरवी और उन्हें पारित करना।
राजनीति में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी ने विधायी प्राथमिकताओं को व्यापक बनाया है। उनके योगदान के कारण ही समाज में महिलाओं की सुरक्षा, घरेलू हिंसा के विरुद्ध कड़े कानून और संपत्ति में समान अधिकार जैसे विषयों पर गंभीर चर्चा और कानून निर्माण संभव हो पाया है। महिला राजनेताओं ने इन सामाजिक बुराइयों के खिलाफ निरंतर आवाज उठाई है और सरकार को संवेदनशील नीतियां बनाने के लिए प्रेरित किया है। यह योगदान न केवल महिलाओं के जीवन को सुरक्षित बनाता है, बल्कि पूरे समाज को अधिक प्रगतिशील और न्यायसंगत बनाने की दिशा में कार्य करता है।

200. (A) सचिव विभाग का प्रशासनिक प्रमुख होता है, जबकि आयुक्त बहु-जिला क्षेत्र में प्रशासन की देखरेख करता है।
सचिव और आयुक्त के बीच का संबंध प्रशासनिक स्तरों के बीच एक स्पष्ट कार्य विभाजन को दर्शाता है। सचिव सचिवालय में स्थित होता है और पूरे राज्य के लिए नीतियां बनाने और विभागों के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होता है। दूसरी ओर, आयुक्त क्षेत्रीय स्तर पर एक संभाग का प्रमुख होता है जिसमें कई जिले शामिल होते हैं। आयुक्त का मुख्य कार्य सचिवालय द्वारा बनाई गई नीतियों को अपने क्षेत्र में प्रभावी ढंग से लागू करवाना और विभिन्न कलेक्टरों के कार्यों का पर्यवेक्षण करना है। यह पदानुक्रम शासन में एकरूपता और नियंत्रण की निरंतरता सुनिश्चित करता है।

201. (C) राज्य सचिवालय
मध्य प्रदेश में राज्य सचिवालय वह सर्वोच्च प्रशासनिक संस्थान है जो मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद के लिए मुख्य प्रशासनिक केंद्र के रूप में कार्य करता है। इसका नेतृत्व मुख्य सचिव द्वारा किया जाता है। सचिवालय का मुख्य कार्य मंत्रिमंडल की बैठकों का संचालन करना, नीतिगत निर्णयों के कार्यान्वयन की निगरानी करना और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करना है। यह सरकार का तंत्रिका केंद्र है जहाँ राज्य के भविष्य को आकार देने वाले महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं और उन्हें प्रशासनिक आदेशों में बदला जाता है ताकि उनका राज्यव्यापी क्रियान्वयन संभव हो सके।

202. (B) उन्हें सौंपे गए कार्यों को करना, जैसे स्थानीय संपत्तियों का रखरखाव और योजनाओं का क्रियान्वयन।
ग्रामीण स्थानीय निकायों की सफलता उनके वित्तीय स्वास्थ्य पर पूर्णतः निर्भर करती है। यदि पंचायतों के पास पर्याप्त धन उपलब्ध नहीं है, तो वे गाँव की सड़कों की मरम्मत, स्वच्छता और पेयजल जैसे बुनियादी नागरिक कार्यों को करने में असमर्थ रहती हैं। वित्तीय मजबूती उन्हें राज्य सरकार पर निर्भरता से बचाती है और उन्हें स्थानीय प्राथमिकताओं के अनुसार स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम बनाती है। पर्याप्त संसाधनों के बिना, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का उद्देश्य अधूरा रह जाता है और विकास के लाभ ग्रामीण आबादी तक प्रभावी ढंग से नहीं पहुँच पाते हैं।

203. (A) केवल 1 और 3
विकास की राजनीति मध्य प्रदेश में एक सक्रिय प्रक्रिया है जहाँ संसाधनों का आवंटन चुनावी रणनीतियों और जन-समर्थन जुटाने के लिए किया जाता है। यह प्रक्रिया पूरी तरह तकनीकी नहीं होती, बल्कि इसमें राजनीतिक लाभ-हानि का विचार भी शामिल होता है। इसके कारण अक्सर विभिन्न क्षेत्रों और समुदायों के बीच इस बात को लेकर प्रतिस्पर्धा और संघर्ष होता है कि विकास का लाभ किसे और कहाँ मिलेगा। विकास परियोजनाओं का उपयोग अक्सर राजनीतिक वैधता प्राप्त करने और मतदाताओं के बीच अपनी पैठ मजबूत करने के एक शक्तिशाली और प्रभावी माध्यम के रूप में किया जाता है।

NODIA

भूमिका विशिष्ट विभागों के प्रबंधन और नीति निर्धारण में होती है, जो सचिवालय के माध्यम से कार्य करते हैं। आयुक्त का पद क्षेत्रीय प्रशासन में महत्वपूर्ण है क्योंकि वह एक संभाग के भीतर आने वाले कई जिलों के कलेक्टरों के कार्यों का पर्यवेक्षण और समन्वय करता है। यह स्पष्ट प्रशासनिक विभाजन सुनिश्चित करता है कि राज्य की नीतियां और क्षेत्रीय क्रियान्वयन दोनों सुचारु रूप से चलें और शासन में जवाबदेही और स्पष्टता निरंतर बनी रहे।

188. (C) मध्य प्रदेश में स्थानीय स्वशासन।
स्थानीय स्वशासन में अक्सर निर्वाचित प्रतिनिधियों और नियुक्त अधिकारियों के बीच वैचारिक टकराव देखा जाता है। प्रतिनिधि जनता की मांगों को तत्काल पूरा करना चाहते हैं, जबकि अधिकारी सरकारी नियमों और बजटीय सीमाओं का पालन करने के लिए बाध्य होते हैं। यह तनाव शासन की प्रक्रिया में एक बड़ी चुनौती है क्योंकि इन दोनों पक्षों के बीच बेहतर सामंजस्य के बिना विकास कार्यों को सफलतापूर्वक और नियमबद्ध तरीके से जमीन पर उतारना बहुत कठिन हो जाता है। सुशासन के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों और नौकरशाही का परस्पर सहयोग अनिवार्य और अपरिहार्य है।

189. (B) प्रशासनिक और विकासात्मक सीमाओं के इर्द-गिर्द की राजनीति।
नए जिले की मांग करना विकास और प्रशासन की राजनीति का एक सामान्य पहलू है। लोगों का मानना होता है कि एक स्वतंत्र जिला बनने से उनके क्षेत्र को अधिक बजट, बेहतर बुनियादी ढांचा और प्रशासनिक पहुँच प्राप्त होगी। यह मांग अक्सर क्षेत्रीय पहचान और आर्थिक आकांक्षाओं से प्रेरित होती है। सरकार के लिए नया जिला बनाना केवल प्रशासनिक निर्णय नहीं है, बल्कि इसके लिए बड़े वित्तीय संसाधनों और राजनीतिक संतुलन की आवश्यकता होती है। ऐसी रैलियां जनता की उन आकांक्षाओं को प्रदर्शित करती हैं जो सीधे शासन के ढांचे और कार्यशैली को प्रभावित करती हैं।

190. (A) यह सुनिश्चित करना कि सत्ता की संरचनाओं में उनका प्रतिनिधित्व और आवाज हो।
पिछड़े वर्गों के राजनीतिक सशक्तिकरण का उद्देश्य लोकतंत्र को अधिक समावेशी बनाना है। जब इन वर्गों के लोग पंचायत और नगर निकायों के माध्यम से सत्ता के पदों पर पहुँचते हैं, तो वे अपनी विशिष्ट समस्याओं को बेहतर ढंग से उठा सकते हैं और नीति निर्माण को प्रभावित कर सकते हैं। यह सशक्तिकरण उन्हें केवल मतदाता से बदलकर निर्णय लेने वाला सक्रिय भागीदार बनाता है। यह प्रक्रिया समाज में शक्ति संतुलन को अधिक न्यायपूर्ण बनाने और ऐतिहासिक रूप से वंचित रहे समुदायों को शासन की मुख्यधारा में समान और सम्मानजनक भागीदारी प्रदान करने के लिए आवश्यक है।

191. (B) जिला स्तर पर शासन का संपूर्ण संस्थागत ढांचा, जिसका नेतृत्व कलेक्टर करता है।
जिला प्रशासन राज्य सरकार की वह महत्वपूर्ण इकाई है जो सीधे जनता से जुड़ी होती है। इसमें राजस्व, कानून-व्यवस्था, कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे सभी प्रमुख विभागों का नेटवर्क शामिल होता है। कलेक्टर इस पूरे तंत्र का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है जो विभिन्न विभागों के बीच समन्वय सुनिश्चित करता है और शासन की नीतियों को क्षेत्रीय स्तर पर लागू करता है। यह ढांचा स्थानीय समस्याओं के समाधान और विकास परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पूर्णतः जिम्मेदार होता है, जिससे शासन की पहुँच गाँव-गाँव तक सफलतापूर्वक संभव हो पाती है।

192. (A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी एक परिवर्तनकारी प्रक्रिया है, लेकिन यह चुनौतियों से मुक्त नहीं है। कई महिला प्रतिनिधियों को प्रशासनिक ज्ञान की कमी और परिवार के पुरुषों के हस्तक्षेप का सामना करना पड़ता है। इसके बावजूद, यह एक निर्विवाद तथ्य है कि उनकी उपस्थिति से ग्रामीण विकास की प्राथमिकताओं में बड़ा सकारात्मक बदलाव आया है। उन्होंने पेयजल, स्वच्छता, पोषण और बाल शिक्षा जैसे बुनियादी मानवीय विकास के मुद्दों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया है, जिससे ग्रामीण जीवन में गुणात्मक सुधार हुआ है और शासन अधिक मानवीय और संवेदनशील बना है।

NODIA

193. (B) P-3, Q-4, R-1, S-2
सचिवालय राज्य प्रशासन का तंत्रिका केंद्र है जहाँ सभी प्रमुख नीतियां बनती हैं। स्थानीय सरकार में स्वायत्तता का अर्थ है कि इन निकायों को एक कानूनी ढांचे के भीतर स्वतंत्र रूप से कार्य करने की स्वतंत्रता हो। वंचित वर्ग वे समूह हैं जिन्होंने लंबे समय तक सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार का सामना किया है और जिन्हें विशेष सहयोग की आवश्यकता है। विकास की राजनीति तब स्पष्ट होती है जब राजनीतिक लाभ के लिए विशेष परियोजनाओं और संसाधनों का रणनीतिक आवंटन किया जाता है। ये सभी तत्व मिलकर मध्य प्रदेश की जटिल शासन व्यवस्था को परिभाषित करते हैं।

194. (C) कलेक्टर के पास जिले के भीतर शक्तियों की एक विस्तृत श्रृंखला और महत्वपूर्ण अधिकार होते हैं।
कलेक्टर के पद की व्यापकता और उसके जिले में सर्वव्यापी प्रभाव को प्रशासनिक साहित्य में विशेष स्थान दिया गया है। एक ही पद में राजस्व अधिकारी, कार्यकारी मजिस्ट्रेट और विकास समन्वयक की शक्तियों का निहित होना उसे अत्यंत प्रभावशाली बनाता है। जिले की हर महत्वपूर्ण घटना या सरकारी योजना के केंद्र में कलेक्टर होता है। यह पद प्रशासन में त्वरित निर्णय लेने और विभिन्न विभागों को नियंत्रित करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे जिले के भीतर उसकी स्थिति एक सर्वोच्च प्रशासनिक प्राधिकारी के रूप में पूरी तरह स्थापित हो जाती है।

195. (A) बस्ती की जनसंख्या और शहरी स्वरूप।
मध्य प्रदेश में नगरीय निकायों का वर्गीकरण क्षेत्र की आबादी और आर्थिक गतिविधियों की प्रकृति के आधार पर किया जाता है। नगर निगमों का गठन बड़े महानगरों के लिए किया जाता है जहाँ जनसंख्या बहुत अधिक होती है। नगर पालिकाएं मध्यम शहरों के लिए और नगर पंचायतें उन छोटे क्षेत्रों के लिए होती हैं जो ग्रामीण से शहरी स्वरूप में बदल रहे हैं। यह व्यवस्था

212. (D) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।
ग्रामीण और शहरी स्थानीय स्वशासन की संरचनाएं और उनके कार्य एक जैसे नहीं हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पंचायती राज अधिनियम लागू है, जबकि शहरों के लिए नगर पालिका अधिनियम कार्य करता है। गाँवों में खेती और कृषि आधारित बुनियादी ढांचे पर ध्यान दिया जाता है, जबकि शहरों में स्वच्छता, जल आपूर्ति और शहरी योजना जैसी नागरिक सुविधाएं प्रमुख होती हैं। इन दोनों निकायों के अधिकार, शक्तियां और वित्तीय स्रोत भी अलग-अलग हैं ताकि वे अपनी आबादी की विशिष्ट समस्याओं का प्रभावी ढंग से समाधान कर सकें और क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित हो सके।

213. (A) यह राज्य के प्राधिकार को चुनौती देता है और इसमें शासन, विकास एवं अधिकारों के प्रश्न शामिल हैं।
नक्सलवाद केवल एक आपराधिक समस्या नहीं है, बल्कि यह एक गंभीर राजनीतिक चुनौती है क्योंकि यह राज्य की लोकतांत्रिक व्यवस्था और उसकी संप्रभुता को चुनौती देता है। यह आंदोलन उन बुनियादी मुद्दों पर आधारित है जो संसाधनों के असमान वितरण, सामाजिक अन्याय और सुदूर क्षेत्रों में प्रभावी शासन की कमी से जुड़े हैं। जब तक राज्य इन राजनीतिक और सामाजिक-आर्थिक जड़ों को नहीं पहचानता, तब तक इसे केवल सुरक्षा उपायों से हल नहीं किया जा सकता। अतः, इस पर विमर्श में विकास और अधिकारों की मांग हमेशा केंद्रीय भूमिका में रहती है।

214. (A) वंचित वर्गों के लिए सशक्तिकरण की राजनीति।
सरकारी नौकरियों में आरक्षण बढ़ाना सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने और वंचित समूहों को शासन में उचित हिस्सेदारी देने का एक शक्तिशाली राजनीतिक साधन है। यह कदम पिछड़े वर्गों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुधारने के व्यापक राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा है। ऐसी नीतियां न केवल इन समूहों को मुख्यधारा में लाती हैं, बल्कि यह राजनीतिक दलों के लिए अपनी समावेशी छवि बनाने और एक बड़े मतदाता वर्ग का समर्थन प्राप्त करने में भी सहायक होती हैं। यह राज्य की सत्ता संरचना में विविधता लाने का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावी माध्यम है।

215. (C) ब्रिटिश राजतंत्र में उत्तराधिकार के नियम।
विकास की राजनीति पूरी तरह से राज्य के आंतरिक आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित होती है। सिंचाई, उद्योग और जन-कल्याणकारी योजनाएं इसके केंद्र में हैं क्योंकि इनका सीधा प्रभाव राज्य की अर्थव्यवस्था और जनता के जीवन पर पड़ता है। इसके विपरीत, विदेशी राजशाही के उत्तराधिकार नियम भारतीय गणतंत्र या मध्य प्रदेश की आधुनिक शासन व्यवस्था के लिए पूरी तरह अप्रासंगिक हैं। राज्य की राजनीति का मुख्य विमर्श स्थानीय संसाधनों के उचित आवंटन और क्षेत्रीय विकास की मांगों तक सीमित रहता है, जिसका बाह्य राजशाही से कोई संबंध नहीं होता है।

216. (B) राज्य प्रशासन के शीर्ष पर महिलाओं का योगदान।
मुख्य सचिव का पद राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था का सर्वोच्च शिखर है। इस पद पर एक महिला की नियुक्ति यह संदेश देती है कि नेतृत्व की क्षमता लिंग आधारित नहीं है और महिलाएं प्रशासन के सबसे जटिल और चुनौतीपूर्ण कार्यों को संभालने में पूरी तरह सक्षम हैं। यह अन्य महिला लोक सेवकों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है और पूरे प्रशासनिक तंत्र में लैंगिक संवेदनशीलता को बढ़ावा देता है। ऐसी ऐतिहासिक नियुक्तियां समाज में महिलाओं की बदलती भूमिका और उनके सशक्तिकरण की दिशा में राज्य की प्रगति का एक जीवंत और सशक्त प्रमाण होती हैं।

217. (A) 2, 4, 1, 3
शासन की प्रक्रिया में सबसे पहले सचिवालय में कैबिनेट द्वारा नीतिगत निर्णय लिया जाता है। इसके बाद, आयुक्त कार्यालय इस नीति को अपने संभाग के कलेक्टरों तक प्रसारित करता है। जिला स्तर पर, कलेक्टर इस योजना के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा करता है और आवश्यक समन्वय सुनिश्चित करता है। अंत में, जमीनी स्तर पर ग्राम पंचायत वास्तविक लाभार्थियों की पहचान कर योजना को लागू करती है। यह क्रम स्पष्ट करता है कि मध्य प्रदेश में कोई भी सरकारी योजना राज्य की राजधानी से शुरू होकर गाँव के अंतिम व्यक्ति तक किस प्रकार पहुँचती है।

218. (C) सहजीवी लेकिन घर्षण के प्रति संवेदनशील, जिसमें नौकरशाही निष्पादन एवं विशेषज्ञता प्रदान करती है और प्रतिनिधि लोकतांत्रिक वैधता प्रदान करते हैं।
स्थानीय शासन की सफलता निर्वाचित प्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच के संतुलन पर टिकी है। अधिकारी तकनीकी नियमों और बजट की सीमाओं को समझते हैं, जबकि प्रतिनिधि जनता की तत्काल आवश्यकताओं और भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये दोनों एक-दूसरे के बिना अधूरे हैं, लेकिन अक्सर उनके कार्यक्षेत्र को लेकर टकराव की स्थिति बनी रहती है। एक कुशल प्रशासन वह है जहाँ ये दोनों अंग एक-दूसरे की सीमाओं का सम्मान करें और सामान्य जन-कल्याण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करें, जिससे विकास की गति निरंतर बनी रहे।

219. (A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
मुख्य सचिव मध्य प्रदेश के प्रशासनिक ढांचे का सर्वोच्च अधिकारी होता है। उसे सभी सचिवों का प्रमुख इसलिए माना जाता है क्योंकि वह राज्य सचिवालय के सुचारु संचालन के लिए उत्तरदायी है। वह नियमित रूप से सचिवों की बैठकों की अध्यक्षता करता है ताकि विभिन्न विभागों के बीच समन्वय बना रहे और सरकार की नीतियों के क्रियान्वयन में कोई बाधा न आए। उसकी वरिष्ठता और अनुभव उसे पूरे प्रशासन पर नियंत्रण रखने और मुख्यमंत्री को प्रभावी प्रशासनिक सहायता प्रदान करने की शक्ति देते हैं, जिससे वह राज्य प्रशासन का मुख्य केंद्र बन जाता है।

220. (A) इसके स्वयं के वित्तीय संसाधन और राज्य से समय पर अनुदान।
किसी भी बड़ी शहरी परियोजना के सफल होने के लिए निरंतर और पर्याप्त वित्त का होना अनिवार्य है। नगर निगमों के पास प्रायः स्वयं के इतने संसाधन नहीं होते कि वे भारी निवेश वाले

Downloaded from www.pdf.tube

204. (B) सुशासन और विकास की पहुंच सुनिश्चित करके स्थानीय आबादी का विश्वास जीतना।
नक्सल प्रभावित जिलों में कलेक्टर के लिए सबसे बड़ी चुनौती शासन और जनता के बीच की दूरी को कम करना है। उग्रवाद अक्सर उन क्षेत्रों में पनपता है जहाँ लोग स्वयं को उपेक्षित महसूस करते हैं। अतः, कलेक्टर को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सरकारी योजनाएं, राशन, स्वास्थ्य और शिक्षा का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे। जब स्थानीय निवासी प्रत्यक्ष रूप से शासन का सकारात्मक प्रभाव देखते हैं, तो वे चरमपंथी विचारधारा से दूर होने लगते हैं। जनता का विश्वास पुनः प्राप्त करना ही सुरक्षा चुनौतियों के स्थाई समाधान की पहली सीढ़ी मानी जाती है।

205. (A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
जिला कलेक्टर के पास भू-अभिलेखों के प्रबंधन की जो महत्वपूर्ण शक्ति है, उसकी जड़ें ऐतिहासिक प्रशासनिक परंपराओं में निहित हैं। औपनिवेशिक काल में शासन का मुख्य आधार कृषि से प्राप्त होने वाला राजस्व था, जिसके लिए भूमि के सटीक रिकॉर्ड बनाए रखना अनिवार्य था। इसीलिए जिले के मुख्य अधिकारी को 'कलेक्टर' कहा गया। आज भी, यद्यपि कलेक्टर की भूमिका विकासात्मक हो गई है, लेकिन भूमि विवादों को सुलझाने और राजस्व प्रशासन को सुचारु रूप से चलाने के लिए यह ऐतिहासिक जिम्मेदारी उसके पद का एक अनिवार्य और अटूट हिस्सा बनी हुई है।

206. (A) समुदाय का एक सदस्य विधायक के रूप में चुना जाना और विधानसभा में समुदाय से संबंधित मुद्दों को उठाना।
सशक्तिकरण का वास्तविक अर्थ तब सिद्ध होता है जब कोई वंचित समूह केवल सहायता प्राप्त करने वाला नहीं, बल्कि स्वयं निर्णय लेने वाला बन जाता है। जब उस समुदाय का व्यक्ति लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित होकर विधान सभा में पहुँचता है, तो वह अपने वर्ग की समस्याओं को सीधे नीति-निर्धारकों के समक्ष रख सकता है। यह उसे अपनी नियति स्वयं तय करने की शक्ति प्रदान करता है। राजनीतिक प्रतिनिधित्व न केवल उस समुदाय का आत्मविश्वास बढ़ाता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि राज्य की नीतियों में उनके हितों की कभी भी उपेक्षा न की जाए।

207. (A) आंगनवाड़ी सेवाओं और स्कूल के मध्याह्न भोजन जैसे मुद्दों को प्राथमिकता देना और उनकी निगरानी करना।
पंचायतों में निर्वाचित महिला सरपंचों ने ग्रामीण विकास की प्राथमिकताओं में एक महत्वपूर्ण मानवीय और सामाजिक संवेदनशीलता जोड़ी है। वे उन क्षेत्रों पर अधिक ध्यान केंद्रित करती हैं जो सीधे बच्चों और परिवार के कल्याण से जुड़े होते हैं, जैसे स्कूलों में भोजन की गुणवत्ता और स्वास्थ्य केंद्रों की सक्रियता। उनकी इस सूक्ष्म निगरानी से इन सेवाओं की कार्यक्षमता में काफी सुधार हुआ है। यह योगदान सिद्ध करता है कि महिला नेतृत्व जमीनी स्तर पर भ्रष्टाचार को कम करने और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक लाभार्थियों तक पहुँचाने में अधिक प्रभावी है।

NODIA

208. (A) P-4, Q-3, R-2, S-1
ग्रामीण स्थानीय स्तर पर सरपंच या प्रधान गाँव के शासन का नेतृत्व करते हैं। शहरी स्थानीय स्तर पर महापौर नागरिक प्रशासन के लिए उत्तरदायी होते हैं। जिला स्तर पर कलेक्टर मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है जो जिले की समस्त गतिविधियों का समन्वय करता है। राज्य स्तर पर सचिवालय सर्वोच्च निकाय है जहाँ महत्वपूर्ण नीतियां और निर्णय लिए जाते हैं। यह मिलान मध्य प्रदेश की प्रशासनिक संरचना के विभिन्न स्तरों और उनके संबंधित नेतृत्वकारी पदों के बीच के स्पष्ट और व्यवस्थित कार्यात्मक विभाजन को प्रदर्शित करता है, जो सुशासन के लिए आवश्यक है।

209. (B) राज्य पर मजबूत वित्तीय निर्भरता और राज्य द्वारा प्रतिनियुक्त अधिकारियों की शक्ति।
यद्यपि स्थानीय निकायों को सैद्धांतिक रूप से स्वायत्त माना जाता है, लेकिन व्यवहार में उनकी स्वतंत्रता सीमित है। उनके पास स्वयं के पर्याप्त धन की कमी है, जिससे वे अपनी परियोजनाओं के लिए राज्य के अनुदानों पर पूरी तरह निर्भर रहते हैं। इसके अतिरिक्त, प्रमुख प्रशासनिक पद राज्य द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, जो निर्वाचित प्रतिनिधियों की तुलना में अक्सर राज्य सरकार के प्रति अधिक जवाबदेह होते हैं। यह वित्तीय और प्रशासनिक नियंत्रण स्थानीय निकायों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने से रोकता है, जिससे उनकी स्वायत्तता कई बार केवल प्रतीकात्मक लगती है।

210. (B) मंत्री को निरंतरता और विशेषज्ञ सलाह प्रदान करना, जो राजनीतिक प्रमुख होता है।
राज्य सरकार में सचिव की भूमिका एक अनुभवी मार्गदर्शक की होती है। मंत्री बदलते रहते हैं, लेकिन सचिव एक स्थायी लोक सेवक होने के कारण विभाग को प्रशासनिक निरंतरता और स्थिरता प्रदान करता है। वह जटिल नीतिगत विषयों पर मंत्री को गहन विश्लेषण और डेटा आधारित परामर्श देता है, जिससे सरकार को सही निर्णय लेने में मदद मिलती है। सचिव यह भी सुनिश्चित करता है कि विभाग का कार्य नियमों और कानून के दायरे में हो। यह संतुलन राजनीतिक विजन और प्रशासनिक व्यावहारिकता के बीच एक सफल समन्वय स्थापित करता है, जो शासन हेतु अनिवार्य है।

211. (C) जिले में सभी सरकारी कार्यों के लिए मुख्य कार्यकारी और समन्वयकारी प्राधिकारी।
मध्य प्रदेश में कलेक्टर जिला प्रशासन का वह मुख्य केंद्र है जहाँ शासन की सभी धाराएं आकर मिलती हैं। वह जिले का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी है जो न केवल कानून-व्यवस्था और राजस्व का प्रबंधन करता है, बल्कि विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में विभिन्न विभागों के बीच सामंजस्य भी स्थापित करता है। उसकी स्थिति एक नेतृत्वकर्ता की तरह है जो जिले के संपूर्ण प्रशासनिक दल का मार्गदर्शन करता है। वह सरकार की नीतियों का जमीनी चेहरा है और स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए राज्य सरकार के प्रति सीधे तौर पर जवाबदेह होता है।

बल्कि यह शासन की प्राथमिकताओं को अधिक न्यायपूर्ण और मानवीय बनाती है।

162. (C) कलेक्टर
मध्य प्रदेश में जिला प्रशासन का नेतृत्व कलेक्टर द्वारा किया जाता है। वह जिले का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है जो विभिन्न सरकारी विभागों, जैसे कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा, के कार्यों के बीच सामंजस्य बिठाने के लिए जिम्मेदार है। कलेक्टर की भूमिका एक पुल की तरह है जो राज्य सरकार की नीतियों को सीधे जनता तक पहुँचाता है। वह न केवल विकास कार्यों की निगरानी करता है, बल्कि जिले के समग्र संसाधनों का प्रबंधन भी करता है ताकि शासन के लक्ष्यों को कुशलतापूर्वक और समयबद्ध तरीके से प्राप्त किया जा सके।

163. (C) अविकसित वन और आदिवासी क्षेत्रों में संसाधनों, गरिमा और विकास।
नक्सली समस्या की जड़ें उन क्षेत्रों में हैं जहाँ आधुनिक विकास की किरणें नहीं पहुँच पाई हैं। सुदूर आदिवासी अंचलों में जल, जंगल और जमीन जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण को लेकर गहरा असंतोष रहा है। जब स्थानीय लोगों को लगता है कि उनकी गरिमा और आजीविका के साधनों की उपेक्षा हो रही है, तो चरमपंथी विचारधाराएं वहां अपनी जगह बना लेती हैं। अतः, यह समस्या केवल कानून-व्यवस्था की नहीं, बल्कि न्याय, सम्मान और समावेशी आर्थिक प्रगति की मांग से जुड़ी एक गहरी सामाजिक और राजनीतिक चुनौती मानी जाती है।

164. (B) प्रशासन और विकास योजना को जमीनी स्तर पर लाना।
ग्रामीण स्थानीय स्वशासन का मुख्य उद्देश्य सत्ता का विकेंद्रीकरण करना है ताकि गाँव के लोग स्वयं अपने विकास के भाग्यविधाता बन सकें। इस व्यवस्था के माध्यम से शासन की पहुँच हर घर तक सुनिश्चित होती है। स्थानीय लोग अपनी समस्याओं, जैसे पानी की कमी या स्कूल की मरम्मत, को जिला या राज्य स्तर की तुलना में अधिक प्रभावी ढंग से पहचान और हल कर सकते हैं। यह ढांचा न केवल विकास कार्यों में गति लाता है, बल्कि ग्रामीणों में लोकतंत्र के प्रति विश्वास और शासन में सक्रिय भागीदारी की भावना भी पैदा करता है।

165. (D) राज्य की विदेशी निवेश नीति।
ग्राम पंचायत की सफलता मुख्य रूप से स्थानीय कारकों पर निर्भर करती है, जैसे राज्य सरकार से प्राप्त बजट, ग्रामीणों का सक्रिय सहयोग और सरपंच की नेतृत्व क्षमता। स्थानीय स्तर पर योजना बनाने और उसे लागू करने के लिए ये तत्व अनिवार्य हैं। इसके विपरीत, राज्य की विदेशी निवेश नीति एक वृहद आर्थिक विषय है जो औद्योगिक विकास और अंतरराष्ट्रीय संबंधों से जुड़ा होता है। इस नीति का एक छोटे गाँव की दैनिक विकास योजनाओं, जैसे स्वच्छता या सड़क निर्माण, के क्रियान्वयन पर कोई प्रत्यक्ष या तत्काल प्रभाव नहीं पड़ता है।

166. (B) यह सुनिश्चित करना कि निर्वाचित परिषद द्वारा लिए गए निर्णय नियमों और विनियमों के अनुसार लागू किए जाएं।
शहरी स्थानीय निकायों में नौकरशाही की भूमिका निर्वाचित प्रतिनिधियों की इच्छाशक्ति और सरकारी कानूनों के बीच एक सेतु की तरह है। परिषद नीतियां बनाती है और महापौर उन्हें दिशा प्रदान करते हैं, लेकिन उन्हें व्यावहारिक और कानूनी रूप से लागू करने का दायित्व अधिकारियों पर होता है। वे बजट का सही विनियोग सुनिश्चित करते हैं और यह देखते हैं कि कोई भी कार्य स्थापित प्रक्रियाओं का उल्लंघन न करे। यह प्रशासनिक जाँच और संतुलन प्रणाली शासन में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है, जो नगर निगम की कार्यक्षमता बढ़ाती है।

167. (B) केवल 2 और 3
मुख्य सचिव मध्य प्रदेश का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है, राजनीतिक नहीं। वह मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार के रूप में कार्य करता है और राज्य की पूरी लोक सेवा मशीनरी का मार्गदर्शन करता है। सचिवालय के भीतर, वह सभी विभागों के सचिवों के बीच तालमेल बिठाता है ताकि सरकारी नीतियों के क्रियान्वयन में कोई दोहराव या संघर्ष न हो। वह मंत्रिमंडल की बैठकों का संचालन करता है और यह सुनिश्चित करता है कि शासन के निर्णय विभागों तक समय पर पहुँचें। उसकी भूमिका प्रशासन में स्थिरता और कार्यक्षमता सुनिश्चित करने के लिए अपरिहार्य है।

168. (B) सत्तारूढ़ दल चुनाव से ठीक पहले एक बड़े पुल या कारखाने का उद्घाटन करता है।
'विकास की राजनीति' का सबसे दृश्यमान रूप चुनाव के समय दिखाई देता है जब सरकार अपनी बड़ी उपलब्धियों का प्रदर्शन करती है। सड़कों, पुलों या नई औद्योगिक इकाइयों का उद्घाटन मतदाताओं को यह याद दिलाने का एक तरीका है कि वर्तमान सरकार विकास के प्रति प्रतिबद्ध है। यह रणनीतिक रूप से मतदाताओं के मन में सकारात्मक छवि बनाने और विकास के नाम पर समर्थन जुटाने की एक प्रक्रिया है। ऐसी गतिविधियों के माध्यम से राजनीतिक दल यह सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि वे राज्य को प्रगति के पथ पर ले जाने में पूरी तरह सक्षम हैं।

169. (A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
मध्य प्रदेश में वंचित वर्गों का सशक्तिकरण न केवल एक नैतिक और सामाजिक लक्ष्य है, बल्कि यह एक महत्वपूर्ण राजनीतिक अनिवार्यता भी है। चूंकि ये वर्ग जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा हैं, इसलिए उनका समर्थन किसी भी राजनीतिक दल की सफलता के लिए निर्णायक होता है। उनकी आर्थिक और सामाजिक समस्याओं को दूर करना और उन्हें विकास की मुख्यधारा में शामिल करना चुनावी विमर्श का अनिवार्य हिस्सा बन गया है। अतः, सामाजिक न्याय की नीतियों का निर्माण अक्सर इन समूहों की राजनीतिक आकांक्षाओं और उनके प्रभावी मतदान व्यवहार को ध्यान में रखकर किया जाता है।

170. (C) ग्राम पंचायत
ग्राम स्तर पर स्थानीय प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की होती है। यह निर्वाचित निकाय गाँव की दैनिक जरूरतों जैसे साफ-सफाई, सार्वजनिक नालियों का निर्माण, प्राथमिक शिक्षा की देखरेख और स्थानीय सड़कों के रखरखाव के लिए उत्तरदायी है। ग्राम पंचायत को विकास योजनाओं को चुनने और स्थानीय संसाधनों का प्रबंधन करने की शक्ति प्राप्त है।

Click Here to Buy book on Amazon

कार्य कर सकें, इसलिए वे राज्य सरकार से मिलने वाले विशेष अनुदानों पर निर्भर रहते हैं। यदि बजट आवंटन में देरी होती है या वित्त की कमी आती है, तो परियोजना बीच में अटक सकती है, जिससे लागत बढ़ती है और जनता को असुविधा होती है। अतः, वित्तीय स्वायत्तता और समयबद्ध धन की प्राप्ति शहरी विकास की सफलता के लिए पहली और अनिवार्य शर्त है।

221. (B) जिले के आपराधिक न्याय प्रशासन की अध्यक्षता करना और कानून-व्यवस्था बनाए रखना।
जिला मजिस्ट्रेट के रूप में कलेक्टर के पास जिले में शांति सुनिश्चित करने के लिए व्यापक दंडाधिकारी शक्तियां होती हैं। वह जिले के पुलिस प्रशासन का पर्यवेक्षण करता है और कानून-व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति में आवश्यक आदेश जारी कर सकता है। उसके पास जेलों का निरीक्षण करने और पुलिस थानों के कामकाज की समीक्षा करने का अधिकार भी होता है। राजस्व संग्रहण और विकास कार्यों के अलावा, एक मजिस्ट्रेट के रूप में उसकी यह भूमिका जिले में राज्य की शक्ति और कानून का शासन बनाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी मानी जाती है।

222. (A) केवल 1 और 3
मध्य प्रदेश का राजनीतिक परिदृश्य सामाजिक समावेश और सशक्तिकरण की प्रवृत्तियों को दर्शाता है। जनजातीय और पिछड़े वर्गों का उत्थान चुनावी एजेंडे का एक अनिवार्य हिस्सा है। साथ ही, राजनीति में महिलाओं की सक्रियता और उनका योगदान अब एक स्वीकृत सामाजिक वास्तविकता बन चुका है। हालांकि, राज्य को अभी भी नक्सलवाद जैसी सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जो मुख्य रूप से इसके सीमावर्ती और वनांचल जिलों में केंद्रित है। यह समस्या अभी पूर्णतः समाप्त नहीं हुई है और शासन के लिए एक निरंतर चुनौती बनी हुई है, जो क्षेत्रीय विकास को प्रभावित करती है।

223. (A) आर्थिक संसाधनों और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के आवंटन पर राज्य का नियंत्रण।
विकास की राजनीति का मूल इस बात में निहित है कि सरकार राज्य के बजट और संसाधनों को किन क्षेत्रों या समूहों के लिए आवंटित करती है। सिंचाई, सड़क और बिजली जैसी परियोजनाओं का चयन अक्सर राजनीतिक प्राथमिकताओं और चुनावी लाभ को ध्यान में रखकर किया जाता है। चूंकि सरकार ही इन संसाधनों की मुख्य वितरक है, इसलिए विकास के निर्णय राज्य के राजनीतिक विमर्श और दलों के बीच प्रतिस्पर्धा का मुख्य केंद्र बन जाते हैं। यह प्रक्रिया दर्शाती है कि आर्थिक प्रगति का मार्ग सीधे तौर पर राजनीतिक सत्ता और उसकी प्राथमिकताओं से जुड़ा होता है।

224. (B) सचिव एक स्थायी सिविल सेवक होता, जबकि मंत्री एक अस्थायी, राजनीतिक कार्यपालिका होता है।
राज्य सरकार में सचिव और मंत्री के बीच का मुख्य अंतर उनकी नियुक्ति की प्रकृति और कार्यकाल में है। मंत्री जनता द्वारा निर्वाचित होता है और उसका कार्यकाल सरकार के कार्यकाल या मुख्यमंत्री की इच्छा पर निर्भर करता है, जो उसे एक राजनीतिक नेतृत्व प्रदान करता है। इसके विपरीत, सचिव एक पेशेवर लोक सेवक होता है जो प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से आता है और अपनी सेवानिवृत्ति तक सेवा में बना रहता है। सचिव विभाग को विशेषज्ञता और निरंतरता प्रदान करता है, जबकि मंत्री विभाग को राजनीतिक दिशा और व्यापक नीतिगत दृष्टिकोण प्रदान करता है।

225. (B) 'ग्राम स्वराज' के स्वप्न को साकार करना और सत्ता का विकेंद्रीकरण करना।
पंचायती राज की स्थापना का उद्देश्य लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के विचार को मूर्त रूप देना था। मध्य प्रदेश में इस व्यवस्था ने यह सुनिश्चित किया है कि गाँव के विकास की बागडोर स्वयं ग्रामीणों के हाथ में हो। सत्ता को राज्य की राजधानी से हटाकर सीधे गाँवों तक पहुँचाने से न केवल शासन अधिक पारदर्शी हुआ है, बल्कि स्थानीय समस्याओं का समाधान भी शीघ्र होने लगा है। यह विकेंद्रीकरण लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करता है और समाज के सबसे निचले स्तर पर स्थित व्यक्ति को भी निर्णय लेने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाने का कार्य करता है।

226. (A) P-3, Q-4, R-2, S-1
मध्य प्रदेश के प्रशासन में पदों और उनके कार्यक्षेत्रों का स्पष्ट विभाजन है। मुख्य सचिव पूरे राज्य के प्रशासनिक तंत्र का प्रमुख होता है और सचिवालय का नेतृत्व करता है। महापौर नगर निगम के प्रमुख के रूप में शहर के नागरिक प्रशासन की देखरेख करते हैं। कलेक्टर जिला स्तर पर सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है जो जिले के समस्त कार्यों का समन्वय करता है। सरपंच ग्राम पंचायत का निर्वाचित प्रमुख होता है जो सीधे गाँव के विकास और स्थानीय शासन के लिए उत्तरदायी है। यह पदानुक्रम राज्य में शासन की सुव्यवस्थित और प्रभावी पहुँच सुनिश्चित करता है।

NODIA

227. (A) हैंडपंप के स्थान या गांव की सड़क की मरम्मत पर निर्णय लेने की क्षमता।
ग्राम पंचायत की स्वायत्तता का सबसे व्यावहारिक रूप उनके उन छोटे लेकिन महत्वपूर्ण निर्णयों में दिखता है जो गाँव के दैनिक जीवन को प्रभावित करते हैं। जब कोई पंचायत यह तय करती है कि गाँव में हैंडपंप कहाँ लगाया जाना चाहिए या किस रास्ते की मरम्मत प्राथमिकता पर होनी चाहिए, तो वह अपनी स्वायत्त शक्ति का उपयोग कर रही होती है। ये निर्णय स्थानीय आवश्यकताओं की बेहतर समझ पर आधारित होते हैं, जो राज्य के प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के बिना लिए जाते हैं। यही स्थानीय निर्णय लेने की शक्ति विकेंद्रीकृत लोकतंत्र की वास्तविक पहचान और सफलता का आधार है।

228. (C) विकास और शासन की चुनौती है।
नक्सली समस्या केवल कानून और व्यवस्था की समस्या नहीं है, बल्कि यह उन क्षेत्रों में शासन की अनुपस्थिति और विकास की उपेक्षा का परिणाम है। सुदूर वनांचल क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं और आर्थिक अवसरों की कमी के कारण स्थानीय लोग व्यवस्था से असंतुष्ट हो जाते हैं, जिसका फायदा चरमपंथी गुट उठाते हैं। अतः, इस चुनौती का वास्तविक समाधान केवल पुलिस कार्रवाई में नहीं, बल्कि उन क्षेत्रों में सड़क, शिक्षा,

नियुक्त किए जाते हैं, जिससे इन निकायों पर राज्य का नियंत्रण और प्रभाव बढ़ जाता है। जब तक स्थानीय निकायों के पास अपने राजस्व के पर्याप्त और स्वतंत्र स्रोत नहीं होंगे, तब तक उनकी वास्तविक स्वायत्तता और स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता अत्यंत सीमित ही बनी रहेगी।

246. (B) शहरी राजनीति में महिलाओं का योगदान।
नगर निगमों की विभिन्न समितियों में महिलाओं का नेतृत्व उनके राजनीतिक सशक्तिकरण और शहरी शासन में बढ़ते प्रभाव को दर्शाता है। जब महिलाएं जल, स्वास्थ्य या शिक्षा जैसी समितियों की अध्यक्षता करती हैं, तो वे इन नागरिक सेवाओं के प्रबंधन में एक नई और मानवीय दृष्टि लाती हैं। यह न केवल उनके व्यक्तिगत कौशल को निखारता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि शहरी विकास की नीतियों में महिलाओं और बच्चों की विशिष्ट आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जाए। ऐसी भागीदारी शहरी लोकतंत्र को अधिक संतुलित, संवेदनशील और प्रभावी बनाने की दिशा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है।

247. (B) राज्य सरकार की नीतियों के क्रियान्वयन के लिए प्राथमिक क्षेत्रीय स्तर की एजेंसी।
जिला प्रशासन राज्य सरकार का वह अंग है जो सीधे धरातल पर कार्य करता है। कलेक्टर के नेतृत्व में यह ढांचा सचिवालय द्वारा बनाई गई नीतियों को आम जनता तक पहुँचाने का मुख्य माध्यम है। चाहे वह स्वास्थ्य मिशन हो, शिक्षा अभियान हो या कृषि सहायता, इन सभी का वास्तविक क्रियान्वयन जिला स्तर पर ही होता है। यह प्रशासन न केवल आदेशों को लागू करता है, बल्कि स्थानीय समस्याओं और फीडबैक को सरकार तक पहुँचाता है, जिससे नीतियों में सुधार संभव हो पाता है। इस प्रकार, यह शासन और जनता के बीच की सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक कड़ी है।

248. (A) इसमें शक्ति और संसाधनों का पुनर्वितरण शामिल है, जो स्वाभाविक रूप से राजनीतिक है।
पिछड़े वर्गों का सशक्तिकरण एक गहरा राजनीतिक मुद्दा है क्योंकि यह समाज के पारंपरिक शक्ति ढांचे को बदलने का प्रयास करता है। जब इन वर्गों को आरक्षण या विशेष अवसर दिए जाते हैं, तो यह संसाधनों और निर्णयों में उनकी भागीदारी को बढ़ाता है, जो अक्सर प्रतिस्पर्धी समूहों के बीच बहस का विषय बनता है। राजनीतिक दल इन वर्गों का समर्थन प्राप्त करने के लिए विशेष नीतियां बनाते हैं, जिससे चुनावी समीकरण प्रभावित होते हैं। अतः, सामाजिक न्याय प्राप्त करने की यह प्रक्रिया अनिवार्य रूप से राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और सत्ता के पुनर्संतुलन से गहराई से जुड़ी हुई है।

249. (A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
जिला कलेक्टर की भूमिका संकट के समय सबसे अधिक महत्वपूर्ण और निर्णायक हो जाती है। जब जिला किसी प्राकृतिक आपदा या आपात स्थिति का सामना करता है, तो कलेक्टर ही वह मुख्य अधिकारी होता है जो पुलिस, स्वास्थ्य, राजस्व और अन्य सभी विभागों को एक साथ लाता है। उसके पास संसाधनों को तत्काल सक्रिय करने और राहत कार्य चलाने की दंडाधिकारी शक्तियां होती हैं। संकट प्रबंधन में उसकी तत्परता और प्रभावी समन्वय ही जीवन और संपत्ति की रक्षा सुनिश्चित करता है। यह जिम्मेदारी उसे जिले में शासन के एक अत्यंत विश्वसनीय और शक्तिशाली स्तंभ के रूप में स्थापित करती है।

250. (A) विकास के लिए सुरक्षा बलों और नागरिक प्रशासन के बीच सफल समन्वय पर।
नक्सलवाद जैसी जटिल समस्या को केवल बंदूकों के बल पर हल नहीं किया जा सकता। इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि सुरक्षा बल और जिला प्रशासन मिलकर किस प्रकार कार्य करते हैं। सुरक्षा बल शांति और भयमुक्त वातावरण बनाते हैं, जबकि नागरिक प्रशासन उसी समय सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं पहुँचाकर जनता का विश्वास जीतता है। यदि विकास और सुरक्षा में से कोई भी एक पक्ष कमजोर पड़ता है, तो समस्या बनी रहती है। अतः, इन दोनों के बीच का बेहतर तालमेल ही उग्रवाद को जड़ से समाप्त करने का एकमात्र स्थाई और प्रभावी मार्ग है।

251. (B) सचिवालय नीतियां बनाता है और क्रियान्वयन के लिए जिला प्रशासन को निर्देशित करता है।
सचिवालय और जिला प्रशासन के बीच का संबंध 'मस्तिष्क' और 'हाथ' के जैसा है। सचिवालय राज्य का वह केंद्र है जहाँ मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा व्यापक नीतियां, कानून और बजट तैयार किए जाते हैं। एक बार नीति बन जाने के बाद, उसे जिला कलेक्टरों को भेजा जाता है, जो जिला प्रशासन के माध्यम से उसे जमीनी स्तर पर लागू करते हैं। सचिवालय दिशा-निर्देश देता है और निरंतर निगरानी करता है, जबकि जिला प्रशासन वास्तविक क्षेत्रीय बाधाओं को दूर करते हुए योजनाओं को जनता तक पहुँचाने का कठिन और महत्वपूर्ण कार्य करता है।

252. (C) दायरे में मध्यवर्ती, जो गांवों के एक ब्लॉक को कवर करती है और ग्राम पंचायतों के कार्य का समन्वय करती है।
मध्य प्रदेश में जनपद पंचायत पंचायती राज व्यवस्था की वह मध्यवर्ती कड़ी है जो विकास खंड स्तर पर कार्य करती है। इसकी मुख्य शक्ति विभिन्न ग्राम पंचायतों के बीच तालमेल बिठाने और उनके विकास प्रस्तावों को जिला स्तर तक पहुँचाने में निहित है। यह खंड स्तर पर कृषि, शिक्षा और सामाजिक वानिकी जैसे कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की देखरेख करती है। जनपद पंचायत यह सुनिश्चित करती है कि राज्य और केंद्र की योजनाओं का लाभ गाँवों तक सुव्यवस्थित तरीके से पहुँचे, जिससे यह ग्रामीण प्रशासन में एक महत्वपूर्ण और अनिवार्य कड़ी के रूप में स्थापित होती है।

253. (B) महिलाओं का योगदान, आदिवासियों का सशक्तिकरण और विकास की राजनीति।
जब कोई महिला विधायक आदिवासियों के वन अधिकारों के लिए कानून बनवाती है, तो यह कई सामाजिक-राजनीतिक लक्ष्यों के संगम को दर्शाता है। यह न केवल राजनीति में महिलाओं के प्रभावी नेतृत्व और उनकी संवेदनशीलता का उदाहरण है, बल्कि यह वंचित जनजातीय समुदायों को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने का एक ठोस प्रयास भी है। इसके साथ ही,

Downloaded from www.pdf.tube

237. (C) ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत।
मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था एक सुव्यवस्थित त्रि-स्तरीय ढांचे पर आधारित है। सबसे बुनियादी स्तर पर ग्राम पंचायत होती है जो व्यक्तिगत गाँवों का प्रबंधन करती है। मध्यवर्ती स्तर पर जनपद पंचायत कार्यरत होती है, जो विकास खंड के गाँवों के बीच समन्वय का कार्य करती है। पदानुक्रम में सर्वोच्च स्थान पर जिला पंचायत होती है जो पूरे जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास कार्यों की योजना और निगरानी के लिए उत्तरदायी है। यह संरचना सत्ता के विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित करती है ताकि शासन की पहुँच गाँव-गाँव तक प्रभावी ढंग से और पारदर्शी रूप से हो सके।

238. (A) केवल 2
जिला पंचायत का मुख्य कार्यपालन अधिकारी एक दोहरी जवाबदेही के अंतर्गत कार्य करता है। वह प्रशासनिक रूप से राज्य सरकार के प्रति उत्तरदायी है क्योंकि वह एक नियुक्त लोक सेवक है, लेकिन कार्यात्मक रूप से उसे जिला पंचायत अध्यक्ष के साथ मिलकर काम करना पड़ता है। नौकरशाही का मूल उद्देश्य स्थानीय निकायों को उनके कार्यों में विशेषज्ञ सहायता प्रदान करना है, न कि उन पर नियंत्रण करना। हालांकि, व्यवहार में अधिकारियों और निर्वाचित सदस्यों के बीच शक्ति के संतुलन को लेकर कभी-कभी तनाव उत्पन्न होता है, जो स्थानीय शासन की एक सामान्य प्रशासनिक चुनौती मानी जाती है।

239. (B) केंद्र सरकार
सचिवालय का ढांचा और कार्य राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर लगभग समान सिद्धांतों पर आधारित है। जिस प्रकार मध्य प्रदेश का राज्य सचिवालय राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के बीच समन्वय करता है और मंत्रियों को नीतिगत सहायता प्रदान करता है, ठीक उसी प्रकार केंद्र सरकार का कैबिनेट सचिवालय प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिमंडल के लिए वही कार्य करता है। दोनों ही संस्थान अपने-अपने स्तर पर प्रशासन के 'तंत्रिका केंद्र' हैं जो राजनीतिक कार्यकारिणी और स्थायी नौकरशाही के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करते हैं ताकि सुचारू शासन सुनिश्चित हो सके।

240. (C) विभिन्न प्रकार के कार्यों वाला एक सामान्यज्ञ प्रशासक।
जिला कलेक्टर का पद एक 'सामान्यज्ञ' अधिकारी का होता है, जिसका अर्थ है कि उसके पास किसी एक विशेष तकनीकी क्षेत्र के बजाय प्रशासन के सभी क्षेत्रों की व्यापक समझ होती है। वह एक साथ राजस्व, न्याय, चुनाव, विकास और आपदा प्रबंधन जैसे विविध कार्यों को संभालता है। यह बहुमुखी प्रतिभा उसे जिले के विभिन्न तकनीकी विभागों के बीच बेहतर समन्वय करने और जटिल प्रशासनिक समस्याओं का समाधान निकालने में सक्षम बनाती है। उसकी भूमिका किसी विशेषज्ञ की नहीं, बल्कि एक कुशल प्रबंधक और नेतृत्वकर्ता की होती है जो पूरे जिले का शासन व्यवस्थित ढंग से चलाता है।

241. (B) पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम (पेसा)।
पेसा अधिनियम मध्य प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों के लिए सशक्तिकरण का सबसे महत्वपूर्ण वैधानिक आधार है। यह कानून अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को अभूतपूर्व स्वायत्तता प्रदान करता है, जिससे उन्हें अपने प्राकृतिक संसाधनों, सामुदायिक विवादों और स्थानीय विकास योजनाओं पर पूर्ण नियंत्रण मिलता है। यह आदिवासियों की सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखते हुए उन्हें शासन की मुख्यधारा में सक्रिय भागीदार बनाता है। यह अधिनियम यह सुनिश्चित करता है कि जनजातीय समुदायों पर कोई बाहरी विकास मॉडल थोपा न जाए, बल्कि वे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार स्वयं को विकसित करने हेतु स्वतंत्र रहें।

242. (A) P-3, Q-2, R-4, S-1
सचिवालय मध्य प्रदेश के राज्य स्तर का सर्वोच्च प्रशासनिक संस्थान है जहाँ नीतियां बनती हैं। जनपद पंचायत खंड या मध्यवर्ती स्तर पर ग्रामीण विकास का समन्वय करती है। नगर निगम विशेष रूप से शहरी स्थानीय शासन की इकाई है जो बड़े शहरों का प्रबंधन करती है। जिला प्रशासन जिला स्तर की समस्त गतिविधियों का केंद्र है जिसका नेतृत्व कलेक्टर करता है। यह मिलान शासन के विभिन्न भौगोलिक और प्रशासनिक स्तरों के बीच के स्पष्ट ढांचे को प्रदर्शित करता है, जो मध्य प्रदेश की शासन व्यवस्था को सुव्यवस्थित, प्रभावी और जनोन्मुखी बनाने के लिए अत्यंत आवश्यक और अनिवार्य है।

243. (A) जबकि दूसरे क्षेत्र की उपेक्षा की जा रही हो।
विकास की राजनीति में क्षेत्रीय असंतुलन अक्सर तनाव का कारण बनता है। जब राज्य सरकार अपने सीमित संसाधनों का बड़ा हिस्सा किसी एक विशेष क्षेत्र में बड़ी परियोजनाओं के लिए आवंटित करती है, तो अन्य क्षेत्रों में उपेक्षा और अन्याय की भावना पैदा होती है। यह क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा राजनीतिक दबाव और विवादों को जन्म देती है, जहाँ जनप्रतिनिधि अपने-अपने क्षेत्रों के लिए अधिक बजट और सुविधाओं की मांग करते हैं। सरकार के लिए चुनौती यह होती है कि वह विकास की गति को बनाए रखते हुए सभी क्षेत्रों के बीच संसाधनों का न्यायपूर्ण और संतुलित वितरण सुनिश्चित करे।

244. (D) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।
राज्य सरकार में नेतृत्व के दो अलग-अलग केंद्र होते हैं। मुख्यमंत्री राज्य की निर्वाचित मंत्री परिषद का प्रमुख होता है, जो राजनीतिक नेतृत्व प्रदान करता है और नीतिगत दिशा तय करता है। दूसरी ओर, मुख्य सचिव राज्य की संपूर्ण प्रशासनिक मशीनरी का प्रमुख होता है, जो इन नीतियों को व्यावहारिक रूप से लागू करने के लिए जिम्मेदार है। यद्यपि मुख्यमंत्री प्रशासन पर नियंत्रण रखते हैं, लेकिन मुख्य सचिव वह स्थायी अधिकारी है जो प्रशासन में निरंतरता और अनुशासन सुनिश्चित करता है। इन दोनों के बीच का बेहतर समन्वय ही राज्य के सुचारू शासन का वास्तविक आधार है।

245. (B) वित्तीय संसाधनों और प्रशासनिक कर्मियों के लिए राज्य सरकार पर उनकी निर्भरता।
स्थानीय स्वशासन की स्वायत्तता में सबसे बड़ी रुकावट उनकी स्वयं की संसाधनों की कमी है। पंचायतों और नगरपालिकाओं को अपने अधिकांश विकास कार्यों और दैनिक खर्चों के लिए राज्य सरकार से मिलने वाले अनुदानों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसके अलावा, उनके मुख्य प्रशासनिक अधिकारी भी राज्य द्वारा

NODIA

295. (A) 74वां संविधान संशोधन अधिनियम और संबंधित राज्य नगरपालिका कानून।
शहरी स्थानीय निकायों की शक्तियों और उनके संगठन का मुख्य स्रोत भारतीय संविधान का 74वां संशोधन है। इसी संवैधानिक ढांचे के आधार पर मध्य प्रदेश सरकार ने अपने विशिष्ट नगरपालिका अधिनियम और नियम तैयार किए हैं। ये कानून नगर निगमों, पालिकाओं और पंचायतों के गठन, उनके चुनावों, कार्यकाल और वित्तीय अधिकारों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हैं। यह वैधानिक आधार ही शहरी निकायों को वह स्वायत्तता और कानूनी शक्ति प्रदान करता है जिससे वे अपने शहरों का प्रबंधन करने और नागरिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए एक स्वतंत्र सरकारी इकाई के रूप में कार्य कर सकते हैं।

296. (B) विशुद्ध सुरक्षा-आधारित समाधान बनाम सामाजिक-आर्थिक समाधान की प्रभावकारिता।
नक्सली समस्या के समाधान को लेकर मध्य प्रदेश के राजनीतिक विमर्श में दो मुख्य विचारधाराएं रही हैं। एक पक्ष कड़े पुलिस और सुरक्षा अभियानों के माध्यम से उग्रवाद को जड़ से उखाड़ने पर जोर देता है। वहीं दूसरा पक्ष यह तर्क देता है कि जब तक प्रभावित क्षेत्रों में गरीबी, शोषण और विकास की कमी को दूर नहीं किया जाएगा, तब तक यह समस्या बनी रहेगी। सरकार अक्सर इन दोनों का मेल अपनाती है, लेकिन इनके बीच का संतुलन और प्राथमिकताएं हमेशा एक प्रमुख राजनीतिक बहस का विषय रहती हैं, जो राज्य की आंतरिक सुरक्षा नीति को नया आकार प्रदान करती हैं।

297. (B) 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा।
राजनीति में महिलाओं के योगदान को एक व्यापक और स्थाई आधार इन संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से प्राप्त हुआ। इन कानूनों ने स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए अनिवार्य आरक्षण सुनिश्चित किया, जिससे मध्य प्रदेश की ग्रामीण और शहरी राजनीति की पूरी तस्वीर बदल गई। इसने महिलाओं को न केवल चुनाव लड़ने का अधिकार दिया, बल्कि उन्हें निर्णय लेने के पदों तक पहुँचाया। इस आरक्षण ने पितृसत्तात्मक सामाजिक ढांचों को चुनौती दी और महिलाओं को अपनी नेतृत्व क्षमता और प्रशासनिक कौशल दिखाने के लिए एक संवैधानिक मंच प्रदान किया, जिससे लोकतंत्र अधिक समावेशी और सुदृढ़ बना है।

298. (C) A सही है लेकिन R गलत है।
सचिवालय मध्य प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था का सर्वोच्च नीति-निर्धारक निकाय है, जहाँ पूरे राज्य के लिए महत्वपूर्ण योजनाएं और कानून बनाए जाते हैं। हालांकि, इसके सचिव जनता द्वारा सीधे निर्वाचित नहीं होते; वे संघ या राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियुक्त पेशेवर लोक सेवक होते हैं। सचिवों का चयन उनकी योग्यता, वरिष्ठता और अनुभव के आधार पर किया जाता है। वे निर्वाचित मंत्रियों के अधीन कार्य करते हैं और उन्हें तकनीकी और प्रशासनिक सलाह प्रदान करते हैं, लेकिन उनकी स्वयं की स्थिति स्थायी नौकरशाही का हिस्सा होती है, जो राजनीति से पूर्णतः पृथक होती है।

299. (A) राजनीतिक कार्रवाई और निर्णय लेने के माध्यम से विकास लक्ष्यों का अनुसरण किया जाता है।
'विकास की राजनीति' का तात्पर्य यह है कि विकास कोई निर्वात में होने वाली प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह राजनीतिक प्राथमिकताओं और निर्णयों का परिणाम है। राजनीतिक दल विकास को अपने मुख्य एजेंडे के रूप में अपनाते हैं और इसके माध्यम से जन-समर्थन प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। यह प्रक्रिया दर्शाती है कि बजट कहाँ खर्च होगा, कौन सी परियोजना कहाँ लगेगी और किन समुदायों को लाभ मिलेगा— ये सभी प्रश्न राजनीतिक विमर्श और सत्ता के समीकरणों से गहराई से जुड़े होते हैं। अतः, विकास लक्ष्य प्राप्त करने के लिए दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति और सही निर्णय लेना ही इसकी वास्तविक सफलता की कुंजी है।

300. (C) जमीनी स्तर के लोकतंत्र को मजबूत करना और शासन में प्रभावी स्थानीय भागीदारी को सक्षम बनाना।
स्थानीय स्वशासन के ग्रामीण और शहरी निकायों को बनाने का मूल उद्देश्य सत्ता का विकेंद्रीकरण करना है ताकि शासन केवल राजधानी तक सीमित न रहे। इन संस्थाओं के माध्यम से आम नागरिकों को अपने स्वयं के विकास के निर्णय लेने का अधिकार मिलता है, जिससे शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ती है। स्थानीय लोग अपनी समस्याओं को बेहतर समझते हैं और उनका समाधान भी शीघ्र कर सकते हैं। यह व्यवस्था लोकतंत्र की जड़ों को गाँवों और शहरों तक गहराई से फैलाती है, जिससे प्रत्येक नागरिक राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में एक सक्रिय और सजग भागीदार बन जाता है।

www.nodia.in

Click Here to Buy book on Amazon

यह 'विकास की राजनीति' का एक हिस्सा है जहाँ संसाधनों का अधिकार स्थानीय लोगों को देकर समावेशी प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया जाता है। ऐसी पहल लोकतंत्र को अधिक न्यायसंगत और जमीनी स्तर पर सशक्त बनाने का महान कार्य करती है।

254. (B) केवल 1 और 3
जिला कलेक्टर जिले का मुख्य राजस्व अधिकारी होता है जो भू-अभिलेखों और कर संग्रहण की देखरेख करता है। साथ ही, वह जिला योजना समिति के प्रमुख के रूप में जिले के विकास का खाका तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि, यह कहना गलत है कि उसकी पुलिस पर कोई पर्यवेक्षी भूमिका नहीं है; जिला मजिस्ट्रेट के रूप में उसके पास कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल पर व्यापक अधिकार और जिम्मेदारी होती है। कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक जिले में शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए निकट समन्वय के साथ निरंतर कार्य करते हैं।

255. (B) दीर्घकालिक परियोजनाओं की योजना बनाने में असमर्थता और राज्य द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं पर निर्भरता।
वित्तीय स्वायत्तता की कमी स्थानीय निकायों को भविष्य की बड़ी योजनाओं के लिए पंगु बना देती है। चूंकि उन्हें धन के लिए राज्य सरकार के आवंटन पर निर्भर रहना पड़ता है, इसलिए वे अक्सर केवल उन्हीं कार्यों को कर पाते हैं जिनके लिए राज्य से विशेष अनुदान प्राप्त होता है। इससे उनकी अपनी स्थानीय प्राथमिकताएं उपेक्षित हो जाती हैं और वे अपनी स्वतंत्र विकास दृष्टि विकसित नहीं कर पाते। निरंतर अनिश्चित वित्तीय स्थिति के कारण, वे स्थायी बुनियादी ढांचे के निर्माण के बजाय केवल दैनिक मरम्मती और छोटे कार्यों तक ही सीमित रह जाते हैं।

256. (A) दीर्घकालिक सतत विकास और अल्पकालिक लोकलुभावन उपाय।
विकास की राजनीति में अक्सर एक गहरा द्वंद्व होता है। एक ओर भविष्य की पीढ़ियों के लिए स्थायी बुनियादी ढांचे, जैसे बांध या शोध संस्थान, में निवेश की आवश्यकता होती है, तो दूसरी ओर चुनावी लाभ के लिए तत्काल राहत देने वाली लोकलुभावन घोषणाओं का राजनीतिक दबाव होता है। सरकारों को अक्सर यह कठिन चुनाव करना पड़ता है कि वे सीमित बजट को दीर्घकालिक आर्थिक प्रगति के लिए खर्च करें या तत्काल जन-समर्थन हासिल करने वाली योजनाओं में। इन दोनों के बीच का संतुलन ही राज्य की वास्तविक विकास दर और राजनीतिक स्थिरता को निर्धारित करता है।

257. (B) नगर निगम
मध्य प्रदेश में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के तीन स्पष्ट स्तर हैं: ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर जनपद पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत। ये तीनों संस्थाएं विशेष रूप से ग्रामीण आबादी की आवश्यकताओं और विकास के लिए समर्पित हैं। इसके विपरीत, नगर निगम शहरी स्थानीय स्वशासन का एक हिस्सा है, जिसका गठन केवल बड़े शहरों और महानगरीय क्षेत्रों के प्रबंधन के लिए किया जाता है। ग्रामीण और शहरी शासन के ये ढांचे पूरी तरह अलग अधिनियमों और प्रशासनिक प्रणालियों द्वारा संचालित किए जाते हैं ताकि विशिष्ट स्थानीय समस्याओं का प्रभावी समाधान हो सके।

258. (A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
स्थानीय शासन में नौकरशाही की भूमिका अक्सर विवादास्पद रहती है क्योंकि मुख्य कार्यपालन अधिकारी जैसे पद राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ये अधिकारी नियमों के प्रति अधिक वफादार होते हैं और सीधे राज्य प्रशासन को रिपोर्ट करते हैं, जिससे निर्वाचित प्रतिनिधियों को लगता है कि उनकी शक्तियों को नियंत्रित किया जा रहा है। जब प्रतिनिधियों की राजनीतिक आकांक्षाएं और अधिकारियों की कठोर प्रशासनिक प्रक्रियाएं टकराती हैं, तो स्थानीय निकायों की स्वायत्तता प्रभावित होती है। यह स्थिति शासन में अविश्वास पैदा कर सकती है और विकास कार्यों की गति को बाधित कर सकती है।

259. (B) शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आर्थिक अवसर।
सशक्तिकरण केवल एक राजनीतिक अधिकार नहीं है, बल्कि यह जीवन की उन बुनियादी स्थितियों में सुधार है जो किसी व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने में सक्षम बनाती हैं। मध्य प्रदेश में वंचित वर्गों के लिए केवल आरक्षण पर्याप्त नहीं है; उनके लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं और रोजगार के पर्याप्त अवसर सुनिश्चित करना अनिवार्य है। जब ये समूह शिक्षित और आर्थिक रूप से स्वतंत्र होते हैं, तभी वे अपनी सामाजिक स्थिति को बदल सकते हैं और विकास की प्रक्रिया में बराबर के भागीदार बन सकते हैं। यही समग्र सशक्तिकरण का वास्तविक और स्थाई मार्ग माना जाता है।

260. (C) मुख्य सचिव
मध्य प्रदेश सचिवालय का प्रशासनिक नेतृत्व मुख्य सचिव द्वारा किया जाता है। वह राज्य के संपूर्ण प्रशासनिक ढांचे का सर्वोच्च अधिकारी होता है जो विभिन्न सरकारी विभागों के बीच सामंजस्य और अनुशासन बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। मुख्य सचिव ही वह कड़ी है जो निर्वाचित मुख्यमंत्री और स्थायी लोक सेवा के बीच समन्वय स्थापित करती है। सचिवालय के सुचारू संचालन, फाइलों के निस्तारण और नीतिगत निर्णयों के प्रभावी क्रियान्वयन की देखरेख करना उसी की जिम्मेदारी है। उसकी कार्यकुशलता ही राज्य सरकार की प्रशासनिक दक्षता और विश्वसनीयता को पूर्णतः निर्धारित करती है।

261. (B) पंचायत और नगरपालिका चुनावों में सीटों का आरक्षण।
महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को संस्थागत और व्यापक बनाने में आरक्षण एक मील का पत्थर साबित हुआ है। मध्य प्रदेश ने स्थानीय निकायों में 50% आरक्षण देकर लाखों महिलाओं को सरपंच, पार्षद और अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पदों पर आसीन होने का अवसर प्रदान किया है। इसने न केवल उनकी संख्यात्मक उपस्थिति बढ़ाई है, बल्कि समाज में उनकी नेतृत्व क्षमता को एक वैधानिक पहचान भी दी है। यह आरक्षण महिलाओं को शासन की बारीकियां सीखने और स्थानीय विकास में सक्रिय योगदान देने के लिए एक अनिवार्य और शक्तिशाली मंच प्रदान करता है, जिससे लोकतंत्र सुदृढ़ होता है।

Downloaded from www.pdf.tube

262. (B) P-2, Q-1, R-4, S-3
जिला स्तर पर भूमि अभिलेखों और राजस्व का प्रबंधन कलेक्टर की प्राथमिक जिम्मेदारी है। शिक्षा विभाग का सचिव राज्य स्तर पर शिक्षा संबंधी व्यापक नीतियों का निर्धारण करता है। ग्रामीण स्तर पर साफ-सफाई और स्वच्छता सुनिश्चित करना ग्राम पंचायत का अनिवार्य कार्य है। संभाग स्तर पर आयुक्त कई जिलों के प्रशासनिक कार्यों का पर्यवेक्षण और समन्वय करता है। यह मिलान शासन के विभिन्न स्तरों और उन पर कार्यरत अधिकारियों के विशिष्ट दायित्वों को स्पष्ट करता है, जिससे प्रशासनिक जवाबदेही तय होती है और सरकारी सेवाओं का सुचारु संचालन निरंतर सुनिश्चित होता है।

263. (A) सार्वजनिक व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए आदेश जारी करना।
जिला मजिस्ट्रेट के रूप में कलेक्टर के पास जिले में कानून का शासन बनाए रखने की सर्वोच्च शक्ति होती है। वह शांति भंग होने की स्थिति में कड़े कदम उठा सकता है, जैसे कर्फ्यू लगाना या किसी संदिग्ध गतिविधि पर रोक लगाना। पुलिस बल उसके निर्देशों के अनुसार कार्य करता है ताकि अपराधों को रोका जा सके और नागरिकों की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित हो। यह शक्ति उसे जिले में एक प्रभावी प्रशासक के रूप में स्थापित करती है, जिससे वह किसी भी विषम परिस्थिति में त्वरित और कठोर निर्णय लेकर शांति व्यवस्था को पुनः स्थापित करने में सक्षम होता है।

264. (D) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।
मध्य प्रदेश के संदर्भ में 'नक्सली समस्या' का अर्थ शहरी यातायात से नहीं, बल्कि राज्य के कुछ सुदूर क्षेत्रों में सक्रिय वामपंथी उग्रवाद से है। यह एक आंतरिक सुरक्षा चुनौती है जहाँ चरमपंथी गुट राज्य की सत्ता को चुनौती देते हैं और हिंसक गतिविधियों में संलग्न रहते हैं। यह समस्या मुख्य रूप से उन वनांचल और आदिवासी बहुल जिलों में है जहाँ विकास की कमी रही है। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार सुरक्षा कार्रवाई और सामाजिक-आर्थिक विकास की दोहरी रणनीति अपनाती है ताकि उन क्षेत्रों में पुनः शांति और स्थिरता स्थापित की जा सके।

265. (C) लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण
मध्य प्रदेश में स्थानीय स्वशासन की नींव लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर टिकी है। इसका अर्थ है सत्ता का उच्च स्तर से हटाकर समाज के सबसे निचले स्तर तक वितरण करना ताकि आम जनता शासन में सीधे भाग ले सके। पंचायतों और नगर पालिकाओं के माध्यम से स्थानीय लोगों को अपने विकास की योजनाएं स्वयं बनाने और उन्हें लागू करने का अधिकार दिया गया है। यह व्यवस्था लोकतंत्र को अधिक जीवंत और जनोन्मुखी बनाती है, जिससे शासन की जवाबदेही बढ़ती है और स्थानीय समस्याओं का समाधान अधिक प्रभावी ढंग से स्थानीय स्तर पर ही संभव हो पाता है।

266. (A) विकास की राजनीति।
किसी क्षेत्र को सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र के रूप में विकसित करने का वादा करना 'विकास की राजनीति' का एक स्पष्ट उदाहरण है। यह राजनीतिक दलों द्वारा मतदाताओं को एक प्रगतिशील भविष्य और रोजगार के अवसर दिखाने की रणनीति है। ऐसी घोषणाएं न केवल उस क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि वे राजनीतिक समर्थन और चुनावी बढ़त हासिल करने का एक प्रभावी माध्यम भी होती हैं। यह दर्शाता है कि आधुनिक राजनीति में विकास के मुद्दे किस प्रकार केंद्रीय भूमिका निभाते हैं और राज्य की आर्थिक प्राथमिकताओं को राजनीतिक विमर्श के साथ मजबूती से जोड़ते हैं।

267. (A) सामाजिक बाधाओं को दूर करने और अपने आधिकारिक अधिकारों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की उसकी क्षमता पर।
मध्य प्रदेश में एक महिला सरपंच की सफलता केवल उसके पद पर निर्भर नहीं है, बल्कि उसके दृढ़ निश्चय और नेतृत्व कौशल पर आधारित है। पितृसत्तात्मक समाज में उन्हें अक्सर अनेक बाधाओं और प्रशासनिक उपेक्षा का सामना करना पड़ता है। एक सफल सरपंच वही है जो इन बाधाओं को पार कर स्वयं निर्णय लेती है और गाँव के विकास के लिए सरकारी अधिकारियों के साथ मजबूती से तालमेल बिठाती है। उसकी सक्रियता और जागरूकता ही उसे एक वास्तविक जन-नेता के रूप में स्थापित करती है और ग्रामीण शासन में गुणात्मक परिवर्तन लाकर विकास के मार्ग को प्रशस्त करती है।

268. (C) यह राज्य सरकार का प्रशासनिक मुख्यालय है, जो मंत्रियों को नीतिगत सहायता प्रदान करता है।
सचिवालय मध्य प्रदेश के शासन का तंत्रिका केंद्र है। यह मंत्रियों और स्थायी लोक सेवा का वह संगम स्थल है जहाँ राज्य की भविष्य की योजनाओं और कानूनों का खाका तैयार किया जाता है। यहाँ के अनुभवी अधिकारी मंत्रियों को प्रशासनिक बारीकियां, बजटीय सीमाएं और कानूनी प्रावधानों की जानकारी देते हैं, जिससे सरकार को जटिल निर्णय लेने में मदद मिलती है। सचिवालय यह सुनिश्चित करता है कि शासन के विभिन्न विभागों के बीच समन्वय बना रहे और सरकार की नीतियों को पूरे राज्य में एकरूपता और प्रशासनिक अनुशासन के साथ सफलतापूर्वक लागू किया जा सके।

269. (B) 'जल, जंगल और जमीन' पर अधिकार।
मध्य प्रदेश की राजनीति में जनजातीय सशक्तिकरण का मूल प्रश्न उनके पारंपरिक संसाधनों पर नियंत्रण से जुड़ा है। 'जल, जंगल और जमीन' उनके जीवन, संस्कृति और आजीविका का आधार हैं। आदिवासियों का संघर्ष हमेशा इन संसाधनों को बाहरी शोषण से बचाने और उन पर अपने कानूनी अधिकार प्राप्त करने के इर्द-गिर्द रहा है। पेसा और वन अधिकार अधिनियम जैसे कानूनों का उद्देश्य उन्हें इन संसाधनों का स्वामी बनाना है। यह सशक्तिकरण उन्हें न केवल आर्थिक रूप से मजबूत करता है, बल्कि उन्हें समाज में एक सम्मानजनक और आत्मनिर्भर स्थान भी प्रदान करता है, जो अनिवार्य है।

270. (A) 2, 1, 4, 3
मध्य प्रदेश सचिवालय के प्रशासनिक पदानुक्रम में मुख्य सचिव सर्वोच्च स्थान पर होता है जो पूरे प्रशासन का समन्वय करता है। उसके नीचे किसी विशिष्ट विभाग का सचिव होता है जो उस

NODIA

विभाग की नीतियों के लिए जिम्मेदार है। पदानुक्रम में अगला स्तर उप सचिव का आता है जो सचिव को प्रशासनिक कार्यों में सहायता प्रदान करता है। सबसे नीचे अवर सचिव का पद होता है जो विभागीय कार्यों के दैनिक निष्पादन और फाइलों के प्राथमिक निस्तारण के लिए उत्तरदायी है। यह सुव्यवस्थित संरचना राज्य शासन में स्पष्ट जवाबदेही और कार्यकुशलता सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत आवश्यक है।

271. (C) समन्वयक
जब कलेक्टर विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करता है, तो वह एक सूत्रधार या समन्वयक की भूमिका निभाता है। जिले में कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और लोक निर्माण जैसे कई विभाग स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं, और कलेक्टर यह सुनिश्चित करता है कि ये सभी विभाग आपस में टकराएं नहीं, बल्कि मिलकर विकास के सामान्य लक्ष्यों को प्राप्त करें। वह संसाधनों के उचित बँटवारे और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करता है। इस समन्वय के बिना, सरकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन और जिला प्रशासन की सफलता कभी भी संभव नहीं हो सकती है।

272. (A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
वित्तीय स्वायत्तता ही स्थानीय स्वशासन की वास्तविक शक्ति का आधार है। पर्याप्त धन के बिना, पंचायतों और नगर पालिकाओं को अपनी हर छोटी आवश्यकता के लिए राज्य सरकार के अनुदानों पर निर्भर रहना पड़ता है, जिससे उनकी स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता समाप्त हो जाती है। यदि उनके पास स्वयं का राजस्व नहीं है, तो वे स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार लचीली विकास योजनाएं नहीं बना सकते। अतः, वित्तीय स्वतंत्रता केवल आर्थिक विषय नहीं है, बल्कि यह लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सफल और प्रभावी बनाने के लिए एक अनिवार्य और प्राथमिक शर्त मानी जाती है।

273. (C) मुख्य नगर पालिका अधिकारी और पंचायत सचिव।
स्थानीय स्वशासन में 'नौकरशाही' उन स्थायी सरकारी अधिकारियों के समूह को कहते हैं जो शासन की निरंतरता और तकनीकी विशेषज्ञता सुनिश्चित करते हैं। मुख्य नगर पालिका अधिकारी शहरी निकायों में और पंचायत सचिव ग्रामीण क्षेत्रों में वह मुख्य कड़ी हैं जो निर्वाचित प्रतिनिधियों के निर्णयों को नियमों के अनुसार लागू करते हैं। वे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और उनका कार्यकाल राजनीतिक चुनावों पर निर्भर नहीं होता। ये अधिकारी बजट प्रबंधन, रिकॉर्ड की देखरेख और सरकारी योजनाओं के वैधानिक क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार होते हैं, जो सुचारु संचालन के लिए अपरिहार्य हैं।

274. (B) क्षेत्रीय विकास की राजनीति।
बुंदेलखंड जैसे पिछड़े क्षेत्रों के लिए विशेष आर्थिक सहायता की मांग करना क्षेत्रीय विकास की राजनीति का एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। यह दर्शाता है कि राजनीतिक विमर्श में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। निर्वाचित प्रतिनिधि अपने क्षेत्र की विशिष्ट समस्याओं, जैसे सूखा या गरीबी, के लिए अधिक संसाधनों और निवेश की वकालत करते हैं। ऐसी बहसें न केवल राज्य के बजट को प्रभावित करती हैं, बल्कि सरकार की क्षेत्रीय प्राथमिकताओं को भी तय करती हैं। यह प्रक्रिया संसाधनों के न्यायपूर्ण वितरण और राज्य के सभी हिस्सों के संतुलित विकास के लिए आवश्यक है।

275. (C) ग्राम सभा
मध्य प्रदेश में ग्राम सभा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सबसे सशक्त उदाहरण है। गाँव के सभी पंजीकृत मतदाताओं से बनी यह सभा ही ग्राम पंचायत के वार्षिक बजट और प्रस्तावित विकास योजनाओं की समीक्षा और उन्हें मंजूरी देने की सर्वोच्च शक्ति रखती है। पंचायत द्वारा किए गए कार्यों की जवाबदेही ग्राम सभा के समक्ष ही तय होती है। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि गाँव के संसाधनों का उपयोग ग्रामीणों की सामूहिक इच्छा और स्थानीय प्राथमिकताओं के अनुसार हो। ग्राम सभा की यह शक्ति ही जमीनी स्तर पर पारदर्शिता, जन-भागीदारी और वास्तविक स्वशासन को निरंतर सुदृढ़ करती है।

276. (D) 1, 2 और 3
मध्य प्रदेश का प्रशासनिक ढांचा एक सुव्यवस्थित पदानुक्रम पर आधारित है। आयुक्त एक संभाग का प्रमुख होता है और कई जिलों के कलेक्टरों के कार्यों की निगरानी करता है। सचिव राज्य स्तर पर किसी एक विभाग के प्रशासन और नीति निर्माण का नेतृत्व करता है। इन सबके ऊपर मुख्य सचिव होता है जो पूरे राज्य की लोक सेवा और सचिवालय का प्रमुख होता है। यह संरचना प्रशासन में शीर्ष से नीचे तक नियंत्रण, स्पष्ट समन्वय और जवाबदेही सुनिश्चित करती है, जिससे शासन की नीतियों का पूरे प्रदेश में प्रभावी क्रियान्वयन संभव हो पाता है, जो जन-कल्याण हेतु आवश्यक है।

277. (B) राज्य सरकार को सभी महत्वपूर्ण घटनाक्रमों और जिले की सामान्य स्थिति के बारे में सूचित रखना।
जिले में सरकार की 'आंख और कान' होने का तात्पर्य है कि कलेक्टर को जिले की प्रत्येक गतिविधि पर पकड़ रखनी होती है। उसे जिले में होने वाली राजनीतिक गतिविधियों, सामाजिक तनावों, कानून-व्यवस्था की स्थिति और विकास कार्यों की प्रगति की निरंतर जानकारी राज्य सरकार को देनी होती है। यह सूचना तंत्र सरकार को समय पर सही निर्णय लेने और किसी भी संभावित संकट को टालने में मदद करता है। कलेक्टर की यह भूमिका राज्य की राजधानी और सुदूर जिलों के बीच एक अटूट सूचना सेतु का कार्य करती है, जो प्रभावी और पारदर्शी शासन के लिए अपरिहार्य है।

278. (A) मानवाधिकारों की सुरक्षा और विकास पर ध्यान देने के साथ एक मजबूत सुरक्षा प्रतिक्रिया की आवश्यकता के बीच संतुलन बनाना।
नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह सुरक्षा के कड़े उपायों को अपनाते हुए भी नागरिक अधिकारों और मानवीय गरिमा की रक्षा कैसे करे। केवल बल प्रयोग से समस्या का स्थाई हल नहीं हो सकता, और केवल विकास कार्य सुरक्षा के बिना संभव नहीं हैं। सरकार को ऐसी महीन रेखा पर चलना पड़ता है जहाँ उग्रवादियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई भी हो और साथ ही निर्दोष स्थानीय लोगों का विश्वास भी बना रहे। सुरक्षा और समावेशी विकास का यह

Click Here to Buy book on Amazon

नाजुक संतुलन ही नक्सलवाद के विरुद्ध किसी भी राजनीतिक रणनीति की वास्तविक सफलता निर्धारित करता है।

279. (B) राजनीतिक सशक्तिकरण
पंचायतों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था करना उनके राजनीतिक सशक्तिकरण का एक प्रमुख साधन है। यह आरक्षण उन्हें स्थानीय शासन के पदों पर आसीन होने का वैधानिक अवसर प्रदान करता है, जिससे वे निर्णय लेने की प्रक्रिया में सीधे शामिल हो सकते हैं। जब इन वर्गों के प्रतिनिधि सत्ता में आते हैं, तो वे अपने समुदाय की समस्याओं को अधिक प्रभावी ढंग से उठा सकते हैं और सरकारी संसाधनों के आवंटन को प्रभावित कर सकते हैं। यह प्रक्रिया समाज के परंपरागत शक्ति संतुलन को बदलती है और लोकतंत्र को अधिक न्यायसंगत, समावेशी और वास्तविक प्रतिनिधिमूलक बनाती है।

280. (B) राज्य की राजनीति के उच्चतम स्तर पर महिलाओं का योगदान और सशक्तिकरण।
एक महिला का मुख्यमंत्री बनना यह सिद्ध करता है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में नेतृत्व का शिखर अब लैंगिक सीमाओं से मुक्त हो रहा है। यह न केवल उनकी व्यक्तिगत राजनीतिक क्षमता और दृढ़ इच्छाशक्ति की विजय है, बल्कि यह राज्य की लाखों महिलाओं के लिए एक शक्तिशाली संदेश भी है। ऐसी भूमिका में रहकर वे न केवल पूरे प्रदेश का शासन चलाती हैं, बल्कि नीति निर्माण में महिला कल्याण और सामाजिक सुरक्षा को एक नई दिशा भी प्रदान करती हैं। यह राज्य में महिलाओं के बढ़ते प्रभाव और उनके वास्तविक सशक्तिकरण का सबसे ऊँचा और सबसे प्रभावशाली प्रमाण माना जाता है।

281. (A) राज्य प्रायोजित विकास के संदर्भ में संसाधनों और लाभों के वितरण का निर्धारण।
विकास की राजनीति अनिवार्य रूप से संसाधनों के आवंटन की एक प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया है। इसमें यह तय किया जाता है कि राज्य का बजट किस क्षेत्र, किस परियोजना और किस सामाजिक समूह के लिए खर्च किया जाएगा। चूंकि संसाधन सीमित हैं और मांगें अनंत, इसलिए विकास के निर्णय अक्सर राजनीतिक प्राथमिकताओं और चुनावी उद्देश्यों से प्रेरित होते हैं। यह प्रक्रिया यह भी निर्धारित करती है कि विकास का लाभ किसे मिलेगा और कौन उपेक्षित रह जाएगा। अतः, विकास केवल एक आर्थिक कार्य नहीं है, बल्कि यह सत्ता की राजनीति और जन-हित के बीच का एक जटिल मेल है।

282. (C) पेशेवर सिविल सेवकों द्वारा
मध्य प्रदेश सचिवालय का दैनिक संचालन और प्रशासनिक प्रबंधन मुख्य रूप से वरिष्ठ लोक सेवकों द्वारा किया जाता है। हालांकि नीतियां निर्वाचित मंत्रियों के मार्गदर्शन में बनाई जाती हैं, लेकिन उन्हें व्यावहारिक रूप प्रदान करने, फाइलों का विश्लेषण करने और कानूनी बारीकियों को सुनिश्चित करने का कार्य ये प्रशिक्षित पेशेवर ही करते हैं। लोक सेवक शासन को निरंतरता और विशेषज्ञता प्रदान करते हैं, जिससे सरकार बदलने पर भी प्रशासनिक कार्य बाधित नहीं होते। यह स्थायी नौकरशाही ही सचिवालय के कुशल और अनुशासित कामकाज का मुख्य आधार और राज्य प्रशासन की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है।

283. (B) जिला स्तर पर राज्य और केंद्र सरकारों की नीतियां और कार्यक्रम।
जिला कलेक्टर का कार्यालय शासन की योजनाओं को जमीन पर उतारने वाली मुख्य एजेंसी है। चाहे वह केंद्र सरकार की आवास योजना हो या राज्य सरकार की कृषि प्रोत्साहन नीति, उन सभी का वास्तविक क्रियान्वयन कलेक्टर के नेतृत्व में जिला प्रशासन द्वारा ही किया जाता है। वह यह सुनिश्चित करता है कि आवंटित धन का सही उपयोग हो और लाभ लक्षित जनता तक पारदर्शी रूप से पहुँचे। कलेक्टर का पद सरकार की पहुँच को गाँवों और नागरिकों के द्वार तक संभव बनाता है, जिससे वह पूरे जिले के प्रशासनिक और विकासात्मक प्रबंधन का मुख्य केंद्र बन जाता है।

284. (A) कथन I और कथन II दोनों सही हैं।
मध्य प्रदेश में जिला पंचायत ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के त्रि-स्तरीय पदानुक्रम में सर्वोच्च स्थान रखती है। इसकी मुख्य भूमिका पूरे जिले के ग्रामीण विकास कार्यों की योजना बनाना और उनके लिए बजट का प्रबंधन करना है। यह केवल एक स्वतंत्र निकाय नहीं है, बल्कि इसके पास अपने नीचे की जनपद और ग्राम पंचायतों के कार्यों का पर्यवेक्षण और समन्वय करने की महत्वपूर्ण शक्तियां भी हैं। जिला पंचायत यह सुनिश्चित करती है कि सभी विकास योजनाएं एकीकृत रूप से लागू हों और ग्रामीण शासन के विभिन्न स्तरों के बीच एक प्रभावी और निरंतर प्रशासनिक तालमेल बना रहे।

285. (C) राज्य सरकार पर वित्तीय निर्भरता।
नगर निगमों की वास्तविक स्वायत्तता अक्सर उनकी वित्तीय सीमाओं के कारण प्रभावित होती है। यद्यपि उनके पास बड़े शहरी क्षेत्रों के प्रबंधन की व्यापक शक्तियां हैं, लेकिन अपने अधिकांश खर्चों के लिए उन्हें राज्य सरकार के अनुदानों और करों के हिस्से पर निर्भर रहना पड़ता है। जब तक नगरीय निकायों के पास अपने स्वयं के राजस्व के स्वतंत्र और सुदृढ़ स्रोत विकसित नहीं होते, तब तक वे राज्य के प्रशासनिक और वित्तीय नियंत्रण से पूरी तरह मुक्त नहीं हो सकते। यह आर्थिक निर्भरता उनकी स्वतंत्र विकास योजनाओं और त्वरित नागरिक सेवाओं के क्रियान्वयन में सबसे बड़ी और स्थाई चुनौती मानी जाती है।

286. (A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
कलेक्टर का पद शक्तियों के अनूठे संगम के कारण अत्यंत शक्तिशाली है। वह एक साथ कई भूमिकाएं निभाता है: राजस्व प्रमुख के रूप में वह भूमि और करों का प्रबंधन करता है, जिला मजिस्ट्रेट के रूप में कानून-व्यवस्था बनाए रखता है, और जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में चुनावों का सफल संचालन सुनिश्चित करता है। इसके अतिरिक्त, जिले के सभी विभागों के बीच समन्वय और विकास परियोजनाओं का क्रियान्वयन भी उसी की देखरेख में होता है। यह बहुआयामी प्रकृति उसे जिले में शासन का केंद्र बिंदु और राज्य सरकार का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्रतिनिधि पूर्णतः बनाती है।

NODIA

287. (B) लिंग-संवेदनशील बजट और नीतियों पर ध्यान केंद्रित करना।
राजनीति में महिलाओं की उपस्थिति ने शासन की प्राथमिकताओं में एक मौलिक बदलाव लाया है। महिला प्रतिनिधियों ने यह सुनिश्चित किया है कि सरकारी बजट और नीतियां केवल सामान्य विकास तक सीमित न रहें, बल्कि वे महिलाओं की विशिष्ट आवश्यकताओं, जैसे मातृत्व स्वास्थ्य, कन्या शिक्षा और सुरक्षा, को भी संबोधित करें। इसे जेंडर बजटिंग कहा जाता है, जहाँ प्रत्येक योजना के प्रभाव का आकलन महिलाओं के दृष्टिकोण से किया जाता है। यह योगदान राज्य की नीतियों को अधिक समावेशी, संवेदनशील और सामाजिक रूप से न्यायपूर्ण बनाने की दिशा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ है।

288. (B) P-3, Q-4, R-1, S-2
स्थानीय स्वशासन के क्षेत्र में स्वायत्तता और प्रशासनिक नियंत्रण के बीच का संतुलन हमेशा एक प्रमुख चर्चा का विषय रहा है। नक्सली समस्या मुख्य रूप से सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और प्रभावित क्षेत्रों में त्वरित विकास पहुँचाने की दोहरी चुनौती पर केंद्रित है। राजनीति में महिलाओं की भूमिका को पंचायतों और नगरपालिकाओं में प्राप्त आरक्षण ने एक सुदृढ़ आधार प्रदान किया है। वंचित वर्गों के लिए सशक्तिकरण की मुख्य रणनीति सकारात्मक कार्रवाई और आरक्षण की नीतियों पर आधारित है। ये सभी मुद्दे मिलकर मध्य प्रदेश के वर्तमान सामाजिक-राजनीतिक परिदृश्य को पूरी तरह परिभाषित करते हैं।

289. (C) सरकार के राजनीतिक और प्रशासनिक प्रमुखों के बीच परस्पर विश्वास।
मुख्य सचिव का चयन केवल वरिष्ठता के आधार पर नहीं होता, बल्कि मुख्यमंत्री के साथ उनके बेहतर तालमेल और विश्वास पर भी निर्भर करता है। चूंकि मुख्य सचिव मुख्यमंत्री का मुख्य प्रशासनिक सलाहकार होता है, इसलिए यह आवश्यक है कि दोनों के बीच नीतिगत मुद्दों पर एक जैसा दृष्टिकोण हो। मुख्यमंत्री ऐसे अधिकारी को चुनते हैं जो उनकी विकास दृष्टि को नौकरशाही के माध्यम से प्रभावी ढंग से लागू कर सके। यह आपसी विश्वास ही प्रशासन में त्वरित निर्णय लेने, संकटों का प्रबंधन करने और शासन की पूरी मशीनरी को एक निश्चित दिशा में कुशलतापूर्वक चलाने के लिए अनिवार्य और अपरिहार्य होता है।

290. (C) स्मार्ट सिटी मिशन।
मध्य प्रदेश के शहरों के बीच स्मार्ट सिटी की सूची में शामिल होने के लिए जो प्रतिस्पर्धा देखी जाती है, वह 'विकास की राजनीति' का एक आधुनिक उदाहरण है। प्रत्येक शहर और वहां के जनप्रतिनिधि चाहते हैं कि उनके क्षेत्र को केंद्र और राज्य की बड़ी परियोजनाओं का लाभ मिले, जिससे वहां का बुनियादी ढांचा सुधरे और निवेश आकर्षित हो। यह प्रतिस्पर्धा शहरी विकास की गति को तेज करती है और राजनीतिक दलों के लिए यह दिखाने का अवसर होता है कि उनका क्षेत्र प्रगति के वैश्विक मानकों की ओर बढ़ रहा है। ऐसी योजनाएं चुनावी विमर्श और क्षेत्रीय गौरव का मुख्य हिस्सा बन गई हैं।

291. (B) राज्य सचिवालय और उसके संभाग के भीतर के जिला प्रशासनों के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करना।
मध्य प्रदेश के प्रशासनिक पदानुक्रम में आयुक्त एक मध्यवर्ती अधिकारी है जो संभाग स्तर पर कार्य करता है। उसका मुख्य कार्य राज्य की राजधानी से आने वाले नीतिगत निर्देशों को अपने क्षेत्र के सभी जिलों के कलेक्टरों तक पहुँचाना और उनके क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण करना है। वह न केवल प्रशासनिक कार्यों की निगरानी करता है, बल्कि वह जिलों की समस्याओं और क्षेत्रीय आवश्यकताओं को भी सरकार तक पहुँचाता है। यह पद प्रशासन में अनुभव और नियंत्रण की एक महत्वपूर्ण परत प्रदान करता, जिससे क्षेत्रीय विकास और शासन में बेहतर सामंजस्य और कड़ा अनुशासन सुनिश्चित होता है।

292. (B) ऐतिहासिक अन्याय और संरचनात्मक असमानताएँ।
वंचित वर्गों के सशक्तिकरण का मुख्य लक्ष्य उन सामाजिक और आर्थिक बेड़ियों को तोड़ना है जिन्होंने उन्हें लंबे समय तक पीछे रखा है। यह केवल तात्कालिक सहायता देने के बारे में नहीं है, बल्कि समाज में व्याप्त उन संरचनात्मक कमियों को दूर करने के बारे में है जो उन्हें समान अवसर प्राप्त करने से रोकती हैं। शिक्षा, संसाधनों का वितरण और राजनीतिक भागीदारी के माध्यम से उन्हें सशक्त बनाकर सरकार ऐतिहासिक रूप से हुए अन्यायों की भरपाई करने का प्रयास करती है। यह प्रक्रिया लोकतंत्र को अधिक न्यायसंगत बनाती है और समाज के प्रत्येक सदस्य के लिए प्रगति के नवीन द्वार खोलती है।

293. (A) केवल 1 और 3
मध्य प्रदेश में स्थानीय स्वशासन को संविधान के माध्यम से एक सुदृढ़ आधार प्रदान किया गया है, जो इसे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का एक अनिवार्य हिस्सा बनाता है। हालांकि, इसकी वास्तविक सफलता कई प्रशासनिक कारकों पर निर्भर करती है। पर्याप्त वित्त की उपलब्धता, एक सहायक नौकरशाही और पर्याप्त कार्यात्मक स्वायत्तता ही वे प्रमुख स्तंभ हैं जिन पर पंचायतों और नगरपालिकाओं की कार्यक्षमता टिकी हुई है। इन तत्वों के बीच का बेहतर संतुलन ही यह सुनिश्चित करता है कि शासन की नीतियां जमीनी स्तर पर सफल हों और विकास के लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक प्रभावी ढंग से पहुँच सकें।

294. (B) लोकतांत्रिक प्रक्रिया में महत्व।
जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में कलेक्टर की जिम्मेदारी लोकतंत्र की आधारशिला को सुरक्षित रखना है। जिले में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराना एक अत्यंत जटिल और संवेदनशील कार्य है, जिसमें पूरी प्रशासनिक मशीनरी का उपयोग होता है। कलेक्टर यह सुनिश्चित करता है कि मतदान की प्रक्रिया पारदर्शी हो और जनता बिना किसी भय के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। यह भूमिका उसे केवल एक प्रशासक से ऊपर उठाकर लोकतांत्रिक मूल्यों के रक्षक के रूप में स्थापित करती है, जो देश की शासन प्रणाली में उसके पद के सर्वोच्च महत्व को स्पष्ट रूप से रेखांकित करती है।

Downloaded from www.pdf.tube

स्वास्थ्य और प्रभावी प्रशासनिक पहुँच सुनिश्चित करने में है। शासन की सक्रियता ही चरमपंथ के प्रति जनता के आकर्षण को समाप्त कर सकती है।

229. (D) कथन I गलत है, लेकिन कथन II सही है।
जिला कलेक्टर जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं होता, बल्कि वह एक पेशेवर लोक सेवक होता है। उसकी नियुक्ति संघ या राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित कड़ी परीक्षाओं के माध्यम से होती है। राज्य सरकार इन योग्य भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को जिलों में कलेक्टर के रूप में तैनात करती है। वे राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं और जिले की पूरी प्रशासनिक मशीनरी के प्रति उत्तरदायी होते हैं। कलेक्टर का पद योग्यता और प्रशासनिक अनुभव पर आधारित होता है, न कि राजनीतिक लोकप्रियता या चुनाव की प्रक्रिया पर।

230. (B) स्थानीय स्वशासन में सीटों का आरक्षण, जो राजनीतिक प्रवेश के लिए एक मंच प्रदान करता है।
मध्य प्रदेश में महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण में आरक्षण की नीति ने एक क्रांतिकारी भूमिका निभाई है। पंचायतों और नगरपालिकाओं में महिलाओं के लिए 50% सीटों का आरक्षण उन्हें घर की दहलीज से बाहर निकलकर सार्वजनिक जीवन में नेतृत्व करने का अवसर प्रदान करता है। इस मंच ने न केवल उनकी राजनीतिक समझ बढ़ाई है, बल्कि उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार भी बनाया है। आरक्षण के माध्यम से प्राप्त इस प्रवेश ने समाज में महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण को बदला है और उन्हें अपनी नेतृत्व क्षमता सिद्ध करने का वैधानिक अधिकार प्रदान किया है।

231. (B) नीति निर्माण, पर्यवेक्षण और नियंत्रण।
मध्य प्रदेश सचिवालय राज्य का वह सर्वोच्च प्रशासनिक केंद्र है जहाँ पूरे प्रदेश के लिए नीतियां और कानून बनाए जाते हैं। यहाँ विशेषज्ञ अधिकारी मंत्रियों को आवश्यक डेटा और परामर्श प्रदान करते हैं ताकि शासन के महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा सकें। सचिवालय का कार्य केवल नीति बनाना ही नहीं, बल्कि विभिन्न विभागों के कार्यों का पर्यवेक्षण करना और यह सुनिश्चित करना भी है कि सरकारी आदेशों का पूरे राज्य में सही ढंग से पालन हो रहा है। यह प्रशासन में एकरूपता, नियंत्रण और दिशा-निर्देश देने वाला मुख्य प्रशासनिक तंत्रिका केंद्र है।

232. (A) स्थानीय स्वशासन में वित्त और स्वायत्तता।
जब किसी नगर निगम में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों और राज्य द्वारा नियुक्त आयुक्त के बीच नीतिगत मतभेद होते हैं, तो यह अक्सर स्थानीय स्वायत्तता और प्रशासनिक नियंत्रण के बीच के तनाव को उजागर करता है। जनप्रतिनिधि अक्सर लोकलुभावन या स्थानीय आवश्यकताओं वाली नीतियां चाहते हैं, जबकि आयुक्त सरकारी नियमों और बजटीय सीमाओं का पालन करने के लिए बाध्य होते हैं। यह टकराव यह भी दर्शाता है कि स्थानीय निकायों के पास अपने संसाधनों पर कितना कम नियंत्रण है और वे अपने निर्णयों के क्रियान्वयन के लिए किस प्रकार राज्य की प्रशासनिक मशीनरी पर निर्भर हैं।

233. (B) चुनावों से पहले की अवधि में, नई योजनाओं और परियोजनाओं की घोषणाओं के साथ।
'विकास की राजनीति' का सबसे प्रभावशाली रूप चुनाव के समय प्रकट होता है जब राजनीतिक दल विकास को अपने मुख्य चुनावी वादे के रूप में प्रस्तुत करते हैं। नई सड़कों, पुलों, उद्योगों और जनकल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की जाती है ताकि मतदाताओं को यह विश्वास दिलाया जा सके कि वर्तमान सरकार ही उनकी प्रगति के लिए प्रतिबद्ध है। यह समय परियोजनाओं के श्रेय लेने की होड़ और विकास के नाम पर राजनीतिक समर्थन जुटाने का होता है। ऐसी घोषणाएं राज्य की भविष्य की विकास दिशा और मतदाताओं की प्राथमिकताओं को गहराई से प्रभावित करती हैं।

NODIA

234. (A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।
राजनीति में महिलाओं के आने से शासन के एजेंडे में एक स्पष्ट मानवीय और सामाजिक बदलाव आया है। महिला प्रतिनिधि अक्सर उन बुनियादी जरूरतों पर अधिक ध्यान केंद्रित करती हैं जो सीधे तौर पर परिवार और समाज के स्वास्थ्य से जुड़ी होती हैं। पेयजल की उपलब्धता, बेहतर स्वच्छता सुविधाएं, गुणवत्तापूर्ण बाल शिक्षा और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उनकी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर रहती हैं। उनकी संवेदनशीलता इन विषयों पर अधिक ठोस निर्णय लेने और उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद करती है, जिससे शासन की दिशा अधिक समावेशी और जनोन्मुखी हो जाती है।

235. (D) आर्थिक और सामाजिक रूप से प्रभावशाली उच्च जातियां।
'वंचित वर्ग' की परिभाषा उन समुदायों तक सीमित है जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से समाज के हाशिए पर रहकर भेदभाव और अभाव का सामना किया है। इसमें अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां और अन्य पिछड़ा वर्ग शामिल हैं जिन्हें विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए विशेष सरकारी सहयोग की आवश्यकता है। इसके विपरीत, वे वर्ग जो आर्थिक रूप से संपन्न हैं और समाज में उच्च सामाजिक स्थिति रखते हैं, उन्हें 'वंचित' नहीं माना जा सकता। सशक्तिकरण की नीतियां विशेष रूप से उन लोगों के लिए हैं जो पारंपरिक रूप से संसाधनों और अवसरों से दूर रहे हैं।

236. (A) जिले के सभी विभागों और एजेंसियों को विकास और कल्याण के सामान्य लक्ष्यों की ओर ले जाना।
जिला कलेक्टर की भूमिका एक कुशल नेतृत्वकर्ता जैसी होती है जो जिले में कार्य कर रहे दर्जनों सरकारी विभागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। उसका मुख्य कार्य यह सुनिश्चित करना है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और निर्माण जैसे विभिन्न विभाग एक-दूसरे के कार्यों में बाधा न बनें, बल्कि मिलकर विकास के साझा उद्देश्यों को पूरा करें। वह विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाले प्रशासनिक अवरोधों को दूर करता है और शासन की नीतियों को एकीकृत रूप से जमीन पर उतारता है। इस समन्वय के बिना जिला प्रशासन अपनी पूरी क्षमता से कार्य नहीं कर सकता।

Visit :
www.pdf.tube

Download PDFs For :

- ✓ MPPSC Chapterwise Question Bank
- ✓ KVS/NVS Chapterwise Question Bank
- ✓ KVS/NVS 30 Sample Papers for Tier-II
- ✓ DSSSB TGT Chapterwise Question Bank
- ✓ DSSSB Sample Papers
- ✓ Chapterwise Question Bank
- ✓ JEE NEET Foundation
- ✓ Primary Classes Worksheets
- ✓ Olympiad Guide
- ✓ Sample Papers
- ✓ Previous Year CBSE Papers
- ✓ Previous JEE, NEET and CUET Papers

Nodia Editions LLP

125, Sector 6, Vidhyadhar Nagar, Jaipur 302039

MRP ₹ 650.00

Click Here to Buy book on Amazon